

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

INTERNATIONAL POLITICS

डॉ० प्रभुदत्त शर्मा

एम. ए. (राजनीति एवं इतिहास), पी-एच. डी. (अमेरिका)

एम. पी. ए. (अमेरिका), स्वर्ण-पदक विजेता

सहोदक, राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम समिति एवं सदस्य, एकेडेमिक कौंसिल

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

६

कॉलेज बुक डिपो

83, त्रिपोलिया बाजार (आतिश गेट के पास)

जयपुर-2 (राज०)

© PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publishers
Published by College Book Depot, Tripolia Bazar, Jaipur-2
Printed at Meena Printers, Jaipur.

नए संस्करण की नई छात

‘अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति’ का यह नया संस्करण नए परिवेश में प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। पिछले सभी संस्करणों का पाठ्य-जगत में जो स्वागत हुआ है उससे हमें सदैव उत्साह मिला है। इस संस्करण को पूर्ण रूप से पुनर्गठित और संशोधित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मिदन्त और व्यवहार दोनों ही पक्षों को परिवर्द्धित और प रिमाजित किया गया है। नए संस्करण की कुछ नई बातें इस प्रकार हैं—

- (1) 1982 के प्रथम चरण तक की महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का विवेचन किया गया है।
- (2) कुछ सर्वथा नए अध्याय/टॉपिक्स जोड़े गए हैं, यथा—नव-उपनिवेशवाद, अन्तर्राष्ट्रीय विकास और संयुक्त राष्ट्रसंघ, महाभक्तियाँ और तृतीय विश्व, भारत और उसके पड़ोसी, पूर्वी यूरोप, हिन्द महासागर आदि।
- (3) संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन करते हुए पर्याप्त नवीनतम प्रवृत्तियों और सम्भावनाओं का उद्घाटन किया गया है।
- (4) ‘एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पुनर्जागरण’ नामक अध्याय में पर्याप्त नवीन सामग्री जोड़ी गई है और विश्व की इस्लामी राजनीति का विवेचन किया गया है।
- (5) अधिकाँश विषय-सामग्री के मूल्यांकन पक्ष को अधिक सबल बनाया गया है।
- (6) महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का त्रिपिचम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार पक्ष के चरित्र को एक ही अंशक में प्रस्तुत करने की दृष्टि से विशेष उपयोगी है।
- (7) विद्यार्थियों के हितार्थ अब तक के परीक्षा प्रश्न-पत्र पुस्तक के अन्त में दे दिए हैं।

विषय-सामग्री के प्रस्तुतीकरण में प्राचिकारिक और प्रामाणिक स्रोतों से नहायता ली गई है। सरकारी प्रकाशनों, विदेशी इनामों से प्राप्ता की गई सूचनाओं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं को प्रस्तुत करने वाली महत्वपूर्ण समाचार-पत्र-पत्रिकाओं का पूरा उपयोग किया गया है। विश्वास है कि अपने नए परिवेश में यह पुस्तक पाठकों और छात्रों के लिए अधिक उपयोगी तथा ज्ञानवर्द्धक मिद होगी और पिछले संस्करणों से कहीं अधिक स्वागत इसे मिलेगा।

पुस्तक में गुप्तार के लिए रचनात्मक मुभाव सदैव मह्यं आमन्त्रित है।

आभार

हिन्दी-भाषा में छठी मुद्रविभूषण और श्रेष्ठ पुस्तकों को भी, प्रबन्धी के माहौल में, उपेक्षा की दृष्टि में देना जा रहा है और यहाँ तक कि कई पुस्तकालयों में एक प्रति का भी बिना पाना देना मीर है। ऐसी प्रतिभूषण परिस्थितियों में भी प्रस्तुत पुस्तक ने अपना नाम और स्थान बनाया है, यह सभी हिन्दी-प्रेमियों के लिए उत्साहवर्धक है।

इस पुस्तक के तबोल संस्करण में आठ जो रूप धारण किया है उसमें हमें सर्वधी न्यायमूर्ति डॉ. नागेन्द्रसिंहजी, श्री टी. एन. सतुर्वेदी, डॉ. ए. प्रबन्धी, डॉ. आर. के. प्रबन्धी, डॉ. पी. एन. मसलदान, प्रो. ए. बी. सात, डॉ. के. बी. राय, डॉ. बी. एस. कुदरान, डॉ. बी. पी. वर्मा, डॉ. हरद्वार राय, डॉ. आर. एन. त्रिवेदी, डॉ. आर. सी. प्रसाद, डॉ. सुभाष बाबु, डॉ. बी. आर. पुरोहित, डॉ. एम. डी. मिश्रा, डॉ. एल. पी. सिंह, डॉ. बीरबंजर-प्रसाद सिंह, डॉ. बी. एन. श्रीवास्तव, डॉ. एम. एम. पुरी, डॉ. ए. डी. फत, डॉ. जे. एस. सेन्स, डॉ. रघुवीरसिंह, डॉ. डी. एन. पाठक, डॉ. आर. पी. श्रीवास्तव, डॉ. एन. आर. देशपाण्डे, डॉ. लक्ष्मणसिंह, डॉ. पी. एन. सेठ, डॉ. मुरलीधर भगत, डॉ. डी. पी. सिंह, डॉ. आई. एन. तिवारी, डॉ. सी. पी. गोयल, एवं अन्य विद्वानों से आशीर्वाद एवं सक्रिय सहयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्राप्त हुआ है, हम उनसे हृदय से आभारी हैं।

प्रकाशक

प्राक्कथन

राष्ट्रीय राज्य का विकास मानव सम्पत्ता के विकास की सम्बन्धी कहानी है। इतिहास के इस चरण से अन्तर्राष्ट्रीय राज्य भयवा सप तक पहुँचने का मानव प्रयास अभी भागीरथ प्रयत्न चाहता है। राष्ट्रीय राज्यों का राष्ट्रेतर आचरण जिसे हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कहते आए हैं, दुनिया के छोटे-बड़े राष्ट्रों के सम्मुख इन प्रकार के विकल्प प्रस्तुत करता रहता है जिन्हें कुन मिलाकर हम विषय के अध्येता 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' कहना अधिप पसन्द करते हैं। एक जमाना था जब यूरोपीय महाद्वीप की घटनाओं और शक्ति-अन्तुलन की तकनीकों को विश्व राजनीति माना जाता था। दो विश्व युद्धों ने, जो मूल रूप से यूरोपीय युद्ध थे, नए शक्ति-पुञ्जों को जन्म दिया और सामूहिक सुरक्षा तथा महाशक्ति युग का आरम्भ कर विश्व राजनीति के सम्मुख नए चुनौती क्षेत्र प्रस्तुत किए। 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशकों ने साम्राज्यवाद के पतन तथा एको-एशियाई भुक्ति की जिन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को आरम्भ किया है उनका दूरगामी प्रभाव आज की राष्ट्रेतर राजनीति एवं शक्ति सम्बन्धों पर स्पष्ट है और दृष्टव्य भी। विषयनाम का सकल सपर्यं महाशक्ति अभिनय का एक पटाक्षेप कहा जा सकता है। इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले नए शक्ति-पुञ्ज एवं अगन्तुलन भावी सम्बन्धों की राष्ट्रेतर राजनीति को परिचालित करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन आज इतिहासगत न होकर राजनीति-परक बनने के लिए प्रयत्नशील है। वैज्ञानिकता की कठिनाइयों और सीमाओं को जानते हुए भी वैज्ञानिक अध्ययन विधियाँ एवं पद्धतियाँ विदेश नीतियों की उन शैलियों के अध्ययन में लगी हुई हैं जो राष्ट्रेतर व्यवहार-जनित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को वर्णित करने की अपेक्षा अधिक गहराई से विवेचित करना चाहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वानों द्वारा किया गया इस प्रकार का बहुत सारा अध्ययन हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है, किन्तु दूसरी ओर यह भी सही है कि ये अध्ययन एक अमेरिकी दृष्टि विशेष को लेकर किए गए हैं और उनकी सीमाएँ तथा अपूर्णताएँ भी अपने आप में स्पष्ट हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और उसके बदलते घटनाक्षेत्रों पर प्रभावशाली एवं समीचीनता से लिखना और यह भी हिन्दी माध्यम में, अपने भाग में एक दुप्तर पायें हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के गिद्दान्तों पर जहाँ तक हमें ज्ञान है, हिन्दी माध्यम से यह पहला सम्भोर प्रयाग है। अतः इसका महत्त्व एक दुर्लभताएँ स्पष्ट है और सम्भोर भी।

अपने इस प्रयाग में विषय की सरलता में नियोजित कर अप्रेक्षी में उपलब्ध नवीनतम साहित्य की हिन्दी पाठक के सम्मुख बोधगम्य शैली में प्रस्तुत करने की हमारी चेष्टा रही है। पाठक भी यदि ऐसा ही समझेंगे तो हम मानेंगे कि हमारा श्रम सफल रहा है। प्रस्तुत संस्करण में अब तक के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के नवीनतम घटना-क्षेत्रों और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के जो नए आयाम गुन रहे हैं और पुराने आयाम नया परिवेश धारण कर रहे हैं, उन्हें समीक्षात्मक रूप में प्रस्तुत करने का हमारा प्रयाग रहा है।

हम उन सभी लेखकों के ऋणी हैं जिनके विद्वत्पूरा ज्ञान एवं शक्तियों की सहायता से हमने अपने विश्लेषण को सफल, समीचीन एवं सगतिपूर्ण बनाया है। आशा है प्रस्तुत रचना के प्रकाशन से हिन्दी प्रकाशनों की दुनिया का एक अभाव पूरा होगा और अन्य मानक रचनाओं को प्रकाश में आने की प्रेरणा मिल सकेगी।

प्रभुदत्त शर्मा

अनुक्रमणिका

1 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का परिचय

.....

(An Introduction to International Politics and International Political System)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतन्त्र विषय के रूप में (2), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विकास के चार स्तर (4), प्रथम स्तर (4), द्वितीय स्तर (5), तृतीय स्तर (5), चतुर्थ और वर्तमान स्तर (6), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र (9), अर्थ एवं स्वरूप (9), क्षेत्र (11), नामकरण की समस्या (15), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था (17), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का सपोषण (19), पुरातन व्यवस्था कायम रखना (20), संक्रमणकालीन व्यवस्था को कायम रखना (22), समकालीन व्यवस्था को कायम रखना (24), अन्तर्राष्ट्रीय सौदेबाजी की प्रक्रिया में प्रवृत्तियाँ (30), शक्ति के प्रयोग में प्रवृत्तियाँ (33), वर्तमान विश्व राजनीति के अन्य परिवर्तनशील तत्त्व एवं नई दिशाएँ तथा उलझनें (35), विचार-धाराओं का परिवर्तित रूप (35), बहुकेन्द्रवाद की ओर प्रवृत्ति (36), क्षेत्रीय संगठनों के रूप और प्रकृति में अन्तर (37), विभिन्न देशों के स्तरों में परिवर्तन (37), विश्व संस्था के प्रति परिवर्तित रुख (38), अणुशक्ति के नए स्वामी (39), शीतयुद्ध (40), मध्यपूर्व और सुदूरपूर्व की विशिष्ट स्थिति (41), साम्राज्यवाद का बदलता हुआ स्वरूप (41), युद्धोपरान्त विश्व में समायोग (42), मुटनिरपेक्ष देशों की उत्तरोत्तर बढ़ती भूमिका (42), सम्प्रभु राज्यों की संस्था में वृद्धि (43), अन्य उलझनें (43), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मुक्ति संघर्ष (44)

2 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त : विभिन्न दृष्टिकोण

.....

(Theories of International Politics : Different Approaches)

विभिन्न दृष्टिकोण (47), ऐतिहासिक दृष्टिकोण (47),

राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीति-घातार्थवाद (48),
गमन्यवादी दृष्टिकोण (52), व्यवस्था गमन्यी दृष्टिकोण
(53), नीति विज्ञान गमन्यी दृष्टिकोण (59), क्षेत्र-मिडान्त
(60), गेन तथा गीदेबात्री का मिडान्त (61), शक्ति के गेन
का एक उदाहरण (63), गेन मिडान्त की प्रक्रिया (65), गेन
मिडान्त द्वारा अनुमपान (69), गेन मिडान्त का मूल्यान्त (71),
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामान्य विचारधारा (72), सामान्य मिडान्त
का अर्थ व स्वरूप (73), सामान्य मिडान्त की प्रकृति एवं
उद्देश्य (73), यथार्थवादी मिडान्त (76), मॉर्गेन्थो के दार्शनिक
आधार (77), राजनीतिक यथार्थवाद के छः मिडान्त (78),
यथार्थवादी मिडान्त का आलोचनात्मक समीक्षा (86)

3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान : पुराने और नए विकासों का सर्वेक्षण
(Science of International Politics : A Survey of Old and New
Developments)

92

मॉर्गेन्थो के विचार (92), विभिन्न दृष्टिकोण (93), अन्तर्राष्ट्रीय
राजनीति की विशिष्ट समस्याओं पर विनियम दो. वापतिन का
विश्लेषण (97), ज्ञान प्राप्ति की दिशा में वैज्ञानिक पद्धति (97),
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विशिष्ट समस्याएँ (99), विज्ञान बनाम
परम्परावाद (101), युद्ध द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रहार
(102), परम्परावाद पर प्रत्याक्रमण (104)

4. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति-संघर्ष के रूप में : राष्ट्रीय शक्ति की
अवधारणा

107

(International Politics as a Struggle for Power : Concept of
National Power)

राष्ट्रीय शक्ति क्या है (108), अनियम प्रमुख परिभाषाएँ (108),
राष्ट्रीय शक्ति पर मॉर्गेन्थो के विचार (112), राष्ट्रीय शक्ति की
विशेषताएँ (115), राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप (117), शक्ति के
लिए मध्यम के आधार (120), शक्ति संघर्ष के रूप (122),
प्रियामील राष्ट्रीय शक्ति पर स्प्राउट के विचार (123) सारणी
प्रियामील राष्ट्रीय शक्ति (128)

5. राष्ट्रीय शक्ति का सार और तत्त्व : राष्ट्रीय शक्ति का उदय और
अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय

130

(Essence and Elements of National Power—Evolution of National
Power and International Community)

राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों का वर्गीकरण और प्रकृति (130), राष्ट्रीय
शक्ति के तत्त्वों की मध्यम व्याख्या (134), भूगोल (134),

प्राकृतिक साधन (135), जनसंख्या (135), प्राविधिक ज्ञान (136), विचारधारा (136), मनोबल (137), नेतृत्व (137), राष्ट्रीय शक्ति का उत्थान और पतन (138), राष्ट्रीय शक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में शक्ति स्तर का वर्गीकरण (139)

6 राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व : भूगोल, प्राकृतिक साधन, जनसंख्या एवं प्राविधिक ज्ञान

144

(Elements of National Power : Geography, Natural Resources, Population and Technology)

भूगोल (144), भूगोल तत्त्व के अध्ययन के विभिन्न भाग (145), अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भौगोलिक दृष्टिकोण (149), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल का प्रभाव (154), प्राकृतिक साधन (156), खाद्यान्न (156), वस्त्रा मान (157), जनसंख्या (158), मर्यादात्मक पहलू (159) गुणात्मक पहलू (160) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जनसंख्या का स्थान (161), तकनीकी प्रथवा प्राविधिक ज्ञान (163), तकनीक द्वारा राष्ट्र के स्वरूप में परिवर्तन (164), तकनीक द्वारा राष्ट्रों की शक्ति-स्थिति में परिवर्तन (165), तकनीक द्वारा राष्ट्रों की आक्रमणकारी शक्ति में वृद्धि (166), तकनीक द्वारा राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक अवस्था में परिवर्तन (166), तकनीक द्वारा देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता को धम्यपूर्ण बनाना (167), तकनीक द्वारा विश्व सरकार के प्रयासों को प्रभावित करना (167), तकनीक द्वारा राष्ट्रों की गोपनीयता की समस्या (168) तकनीक द्वारा शीतयुद्ध की प्रेरणा (168), पैडलफोर्ड एवं निकन के अनुसार तकनीकी प्रभाव (168), तकनीकी विकास का आधार (170), प्राविधिक परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (171), राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व के रूप में अक्षुण्ण शासन (175), नीतियों तथा साधनों के सन्तुलन की समस्या (175), साधनों में सन्तुलन की समस्या (176), जनता के समर्थन की समस्या (177), गृह शासन तथा विदेश नीति (180)

7 राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व : विचारधारा, मनोबल एवं नेतृत्व, राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन

181

(Elements of National Power : Ideology, Morale and Leadership, Evolution of National Power)

विचारधारा (181), विचारधारा का अभिप्राय (182), विचारधारा का कार्य (183), विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति के सन्दर्भ रूप में (187), विचारधारा का आश्रय क्यों लिया जाता है (190),

विचारधारा का राष्ट्रीय शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव (192),
विचारधारा और विदेश नीति (193), युद्ध प्रमुख विचारधाराएँ
 (195), विचारधारा सम्बन्धी अनुसन्धान की समस्याएँ (203),
 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य और द्वितीयक (204), नैतिकता
 और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (207), मनोबल (211), मनोबल
 के निर्माण के साधन (212), नेतृत्व (215), नेतृत्व की
 विशेषताएँ (216), शांतिकाल में नेतृत्व (217), युद्धकाल में
 नेतृत्व (217), राष्ट्रीय शक्ति का सु-योग (221), मार्गों की
 विचार (223), मुख्य शक्तियों के नैतिक दृष्टि में, जनसंख्या की
 दृष्टि से और कुल राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से (224)

8 राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन : कूटनीति, प्रचार और
 राजनीतिक युद्ध

226

(Instruments for the Promotion of National Interest : Diplomacy, Propaganda and Political Warfare)

राष्ट्रीय हित का अर्थ (227), राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित
 राष्ट्रीय हित (229), राजनय अथवा कूटनीति (231), कूटनीति
 का अर्थ (232), कूटनीति एवं विदेश नीति (235), कूटनीति
 और अन्तर्राष्ट्रीय कानून (236), कूटनीतिक रणनीति (237),
 कूटनीति के सध्य (237), कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना और
 साम्यता द्वारा राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि (239), राष्ट्रीय हितों की
 अभिवृद्धि में कूटनीतियों का योगदान (241), कूटनीतिक विशेषा-
 धिकार एवं स्वतन्त्रताएँ (244), राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के
 लिए कूटनीति के मूलभूत कार्य (244), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में
 कूटनीति का स्थान (252), कूटनीति के विभिन्न प्रकार (255),
 कूटनीति पर प्रभाव डालने वाले कुछ नए विकास (265), सशस्त्र
 कूटनीति (267), प्रचार (268), प्रचार का अर्थ एवं परिभाषा
 (269), प्रचार एवं कूटनीति (270), प्रचार विदेश नीति के एक
 साधन के रूप में (272), प्रचार के उद्देश्य : राष्ट्रीय हित में वृद्धि
 (272), प्रचार के तरीके (274), प्रस्तुत करने की विधि (274),
 ध्वनिचित्रण विधि (276), अनुसूचित प्रतिप्रिया प्राप्त करने की
 युक्ति (277), स्वीकृति प्राप्त करने के साधन (278), प्रभावशाली
 प्रचार की आवश्यकताएँ (279), सूचना और प्रचार के रूप (281),
 सोवियत रूस का प्रचार यन्त्र (283), संयुक्त राज्य अमेरिका
 का प्रचार यन्त्र (284), सांस्कृतिक सम्बन्ध और विदेश नीति
 (286), राजनीतिक युद्ध (289), राजनीतिक युद्ध का अर्थ
 (289), राजनीतिक युद्ध के साधन (290)

- 9 राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन : साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद एवं युद्ध राष्ट्रीय नीति के एक साधन के रूप में (Economic Instruments for National Policy : Imperialism, Colonialism, Neo-Colonialism, and War as an Instrument of National Policy)

292

राष्ट्रीय नीति के लिए आर्थिक साधन (292), आर्थिक साधन : धर्म और महत्त्व (293), आर्थिक साधनों के निर्धारक तत्व (295), अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जीवन की प्रकृति (296), आर्थिक साधनों के प्रकार (297), आर्थिक युद्ध (305), साम्राज्यवाद (306), साम्राज्यवाद क्या है—धर्म की समस्या (306), साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धान्त (309), साम्राज्यवाद सम्बन्धी कुछ निष्कर्ष (310), साम्राज्यवाद के तीन लक्ष्य (311), साम्राज्यवाद के तीन साधन (314), साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (318), साम्राज्यवाद की नींव के पत्थर (319), साम्राज्यवाद के रूप (324), साम्राज्यवाद का मूल्यमूलक : दोष एवं प्रतिरोध (325), उपनिवेशवाद एवं नव-उपनिवेशवाद (329), उपनिवेशवाद (329), नव-उपनिवेशवाद (330), वर्तमान युग और राष्ट्रीय मुक्ति-प्रान्दोलन (344), राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष की गहनता के कारण (345), राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्तियों के नए पहलू (348), राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में सेना की भूमिका (सेना और राजनीति) (350), युद्ध (354), युद्ध का धर्म (354), सन् 1945-1972 तक भट्टावन युद्ध (356), युद्ध के बारह कारण (357), युद्ध के कार्य (366), सम्पूर्ण युद्ध (369), मानव शक्ति की सम्भावनाएँ (374), युद्ध को रोकने का प्रयास (377)

- 10 राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ : शक्ति सन्तुलन, सामूहिक सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान

379

(Limitations of National Power : Balance of Power, Collective Security and Pacific Settlement of International Disputes)

शक्ति-सन्तुलन (379), शक्ति सन्तुलन की परिभाषाएँ (380), व्यवधारणा का इतिहास (381), शक्ति सन्तुलन की तीन अभिव्यक्तियाँ (384), शक्ति सन्तुलन की प्रस्पष्टता के अनेक धर्म (385), शक्ति सन्तुलन की स्थापना के तरीके (390), शक्ति सन्तुलन तथा राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले अन्य तत्त्व (394), शक्ति सन्तुलन पर माँगें के विचार (394), शक्ति सन्तुलन मिडान्त का मूल्यमूलक (396), सामूहिक सुरक्षा (398), सामूहिक सुरक्षा का धर्म (399), सामूहिक सुरक्षा के विचार का

- विज्ञान (400), सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संयुक्त (401), सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रसंघ (404), सामूहिक सुरक्षा के धर्म के रूप में राष्ट्रसंघ के प्रति साक्ष्य और अमेरिकन दृष्टिकोण (404), राष्ट्रसंघ की प्रभावशालिता (406), सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्रसंघ (407), सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संधियाँ (409), संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में सम्मिलित अनुच्छेद (410), सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था का मूल्यांकन (414), सामूहिक सुरक्षा का प्रादुर्भाव स्वरूप : डॉ. नायडू के विचार (417), सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की पूर्व जड़ें (418), क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा की एक व्यवस्था है ? : डॉ. नायडू के विचार (420), भारत और सामूहिक सुरक्षा का मिश्रण (420), अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधानों की दो श्रेणियाँ (422), शान्तिपूर्ण समाधानों के माधन (423), एक मुश्किल हुई व्यवस्था की ओर (428)

- 11 राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ : अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं विश्व सरकार (Limitations of National Power : International Law and World Government)

433

अन्तर्राष्ट्रीय कानून (433), अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ (433), अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक वास्तविकता है (435), अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार (437), राष्ट्रीय कानून की प्रणालियाँ (439), अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत (440), अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकेंद्रित स्वरूप (441), अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण (442), अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रकार (443), अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे दबाव (445), अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मूल्यांकन (446), विश्व सरकार (448), विश्व सरकार की मान्यता की विशेषताएँ (448), विश्व सरकार की उपयोगिता (450), विश्व सरकार के उपाय और साधन (452), विश्व सरकार की धारणा का मूल्यांकन (455)

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ : निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, एवं विश्व जनमत, अन्तर्राष्ट्रीय विकास और संयुक्त राष्ट्रसंघ (Limitations of National Power : Disarmament International Morality World Public Opinion, International Development and U. N. O.)

456

निःशस्त्रीकरण : अर्थ एवं प्रकार (456), निःशस्त्रीकरण : क्यों (458), शान्ति स्थापना के लिए (458), प्राथमिक कल्याण और पुनर्निर्माण के लिए (459), समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए (459), नैतिक बानाबरण के निर्माण के लिए (460), आणविक संकट में बचने के लिए (460), द्वितीय महायुद्ध से पूर्व

ना निःशस्त्रीकरण के प्रयास (461), राष्ट्रमंडल के बाहर किए गए निःशस्त्रीकरण के प्रयास (461), राष्ट्रमंडल द्वारा किए गए निःशस्त्रीकरण के प्रयास (463), द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में निःशस्त्रीकरण के प्रयास (464), समुक्त राष्ट्रमंडल के बाहरी निःशस्त्रीकरण की व्यवस्था (465), जेनेवा सम्मेलन, 1955 से 1960 तक (466), 1978 में समुक्त राष्ट्र मंत्रि निःशस्त्रीकरण सम्मेलन (470), कार्टर व होम्सबेक द्वारा सन् 2 पर हस्ताक्षर, जून 1979 (472), वर्ष 1980 तथा 1981 की घटनाएँ (472), निःशस्त्रीकरण के सन्दर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति रोमन का विदेशनीतिक भाषण (नवम्बर, 1981) और चार-सूत्री प्रस्ताव (474), निःशस्त्रीकरण की समस्याएँ (478), निःशस्त्रीकरण के मार्ग में कठिनाइयाँ (479), क्या निःशस्त्रीकरण का अर्थ शान्ति है (482), हथियारों के प्रसार का निवृत्त-मिडलान (483), अस्त्र और शान्ति (485), अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता (486), शान्तिकाल में मानव-जीवन की रक्षा (488), युद्धकाल में मानव-जीवन की सुरक्षा (488), शांति युग की नैतिकता (489), अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का मूलोत्पत्ति (491), विश्व जनमत (492), विश्व लोकमत क्या है (493), विश्व की मनोवैज्ञानिक एकता (494), भौतिक एकीकरण की अस्पष्टता या सदिशता (495), राष्ट्रवाद की अस्तित्व (497), अन्तर्राष्ट्रीय विकास और समुक्त राष्ट्रमंडल (499), अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाए रखकर अन्तर्राष्ट्रीय विकास का आधार तैयार करना (499), निःशस्त्रीकरण प्रयत्नों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए वातावरण तैयार करना (500), आर्थिक एवं सामाजिक परिपक्वता अन्तर्राष्ट्रीय विकास (501), विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास (503)

- 13 वर्तमान विश्व की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ : एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका का जागरण, महाशक्तियाँ और तृतीय विश्व
(Contemporary Emerging Trends : Resurgence of Asia and Latin America, Super Powers and the Third World)

513

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियाँ (514), एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में जागरण के कारण (518), एशिया का जागरण : प्रथम युग (प्रारम्भ से 1947 तक), द्वितीय युग (1947 से 1955 तक), तृतीय युग (1955 से 1962 तक), चतुर्थ युग (1962 से मार्च 1982) (520), एशियाई राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण (526), महाशक्तियाँ और एशिया (529), दक्षिण-पूर्वी एशिया-बदलते आर्थिक

समीकरण (533), दक्षिण-पूर्वी एशिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा (536), महाशक्तियों और एशिया में युद्ध का बढ़ता गड्ढा (540), अफ्रीका में जाग्रति (544), अफ्रीका महाद्वीप का परिवर्तन (544), द्वितीय महायुद्ध के बाद स्वतंत्रता की लहर (1945-1974) (545), एकता की भावना आज भी एक गतिविधित्व (549), स्वाधीनता की इन्तजार वाले देश (550), अन्तिम उपनिवेश (554), स्वतन्त्र अफ्रीका-महाद्वीप की समस्याएँ (556), अफ्रीका में साम्यवाद (559), एशिया तथा अफ्रीका के जागरण में समानताएँ और अन्तर (561), एशिया और अफ्रीका के जागरण के प्रतीक महत्वपूर्ण संगठन और सम्मेलन (563), प्रथम एशियायी सम्मेलन, 1947 (563), द्वितीय एशियाई सम्मेलन, 1949 (563), बौद्धिक सम्मेलन, 1955 (564), मोशी सम्मेलन, 1963 (564), अदिम अबाबा सम्मेलन, 1963 (565), अफ्रीकाई एकता सम्मेलन, 1972 (565), अफ्रीकी एकता संगठन (566), अखिल-अफ्रीकावाद (567), अरब नीति (567), कम्पाला सम्मेलन, जुलाई-अगस्त, 1975 (568), अदिम अबाबा का विशेष सम्मेलन (जनवरी 1976) और अंगोला में युद्ध (568), एशियान निम्नर सम्मेलन (फरवरी 1976) (569), एशियान सम्मेलन, अगस्त 1977 (570), अफ्रीकी एकता संगठन का 15वाँ अधिवेशन, जुलाई 1978 (570), अन्तर्राष्ट्रीय दिल्ली सम्मेलन (अक्तूबर 1978) (571), इस्लामी सम्मेलन (फरवरी 1980) (572), अन्य सम्मेलन (574), अफ्रीकायी एकता को हानि पहुँचाने वाले कुछ सम्मेलन (574), जट्टा सम्मेलन, 1972 (574), इस्लामी निम्नर सम्मेलन, 1974 (574), अल्जीरिया का स्वाधीनता संग्राम (577), रुग की अफ्रीकी नीति (579), अफ्रीका के प्रति पश्चिमी यूरोपीय देशों की स्पष्ट नीति की माँग (581), एशिया और अफ्रीका में विदेशी शक्तियों की स्थिति पर आन्द्रेई घोमिको का मयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन, 1978 में भाषण (583), दक्षिण रोडेजिया (एक स्वाधीन जिम्बाब्वे) का संकट (585), ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (585), अरब राज्य सभ : बिस्वाब की ओर (588), लेटिन अमेरिका का जागरण (590), लेटिन-अमेरिका से अभिप्राय (590), लेटिन अमेरिका का स्वाधीन होना (591), 20वीं सदी में लेटिन अमेरिका की मौलिक समस्याएँ, प्रभाव व जागरण (592), अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लेटिन अमेरिका (594),

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लेटिन अमेरिका के महत्त्व में अभिवृद्धि : सम्भावनाएँ व बाधाएँ (597), लेटिन अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका व अन्य क्षेत्र में वामपंथी प्रवृत्तियाँ (598)

14 भारत और उसके पड़ोसी 606

(India and her Neighbours)

भारत और पाकिस्तान (607), नेहरू युग (अगस्त 1947 से मई 1964) (607), शास्त्री युग (मई 1964 से जनवरी 1966) (610), इन्दिरा युग (जनवरी 1966 से मार्च 1977) (612), जनता पार्टी का शासन (मार्च, 1977-दिसम्बर, 1979) (616), श्रीमती गांधी के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद भारत-पाक सम्बन्ध (फरवरी, 1982 तक) (616), भारत और चीन (617), नेहरू युग में भारत-चीन सम्बन्ध (1947-मई, 1964) (617), शास्त्री काल में भारत-चीन सम्बन्ध (मई, 1964-जनवरी, 1966) (620), इन्दिरा काल में भारत-चीन सम्बन्ध (जनवरी 1966-मार्च 1977) (620), जनता शासन काल में भारत चीन सम्बन्ध (मार्च 1966-1979) (621), श्रीमती गांधी के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद भारत चीन सम्बन्ध (फरवरी 1982 तक) (622), भारत और श्रीलंका (622), भारत और नेपाल (624), भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्धों पर भारत सरकार की रिपोर्ट 1980-81 (626), भारत और अफगानिस्तान (626), भारत और बंगलादेश (627), भारत और भूटान (629), भारत और बर्मा (629), भारत और ईरान (630), भारत और मालदीव (630), भारत और नेपाल (631), भारत और पाकिस्तान (632), भारत और श्रीलंका (633), भारत और चीन (634)

15 महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश नीति 636

(Rise of Soviet Union as Super Power and its Foreign Policy)

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक सोवियत संघ के उदय की प्रवृत्तियाँ (636), युद्ध के सोवियत लक्ष्य (640), युद्धकालीन सोवियत कूटनीति (641), पश्चिमी मित्र एवं सोवियत नीति (642), तेहरान सम्मेलन (643), पूर्वी केन्द्रीय यूरोप पर सोवियत विजय (644), चर्चित का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (647), ग्लास सम्मेलन (648), सोवियत रुख और संगुक्त राष्ट्रसंघ (650), जर्मनी का

प्रारम्भमर्षण (651), पूर्वी बेन्द्रीय यूरोप में प्रादेशिक सम्भोजन (652), पोद्मडाम सम्मोजन (653), जापान की हार (655), रुम के पक्ष में महायुद्ध के परिणाम और महाशक्ति के रूप में रुम का उदय (स्टालिन युगीन विदेश नीति (656), मून्याकिन (663), मोलेन्बोव काय (1953-1954) (664), म्प्रुन्चेव काय (1955-1964) (665), म्प्रुन्चेवकापीन विदेश नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ (665), म्प्रुन्चेव-रोमीगिन काय (जनवरी 1964-दिसम्बर 1980) (669), रोमीगिन के बाद नवम्बर 1980 में मार्च 1982 तक मोविषन विदेश नीति (677), मोविषन विदेश नीति का मून्याकिन (679)

16 संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय और उसकी विदेश नीति

680

(Rise of U. S. A. as Super Power and Its Foreign Policy)

संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय (681), दो महायुद्धों के बीच अमेरिका (681), द्वितीय महायुद्ध काल में अमेरिका (685), म्प्रुन्चेव-युग (1945-1952) (687), महायुग तथा धनुषमणिका की नीति (अगस्त 1945-अगस्त 1946) (688), धवरोध की नीति (अगस्त 1946-जून 1950) (689), मुले मर्षण का काल (जून 1950-जुलाई 1951), म्प्रुन्चेव-हॉर-युग (1953-1961) (693), म्प्रुन्चेव युग (1960-1963) (696), म्प्रुन्चेव युग (1964-1968) (699), म्प्रुन्चेव युग (1969-अगस्त 1974), (701), म्प्रुन्चेव युग (अगस्त 1974-1976) (704), म्प्रुन्चेव युग (1977-1980) (708), म्प्रुन्चेव युग और अमेरिकी विदेश नीति (जनवरी 1981 में अब तक) (712), अमेरिकी विदेश नीति का मून्याकिन (714), म्प्रुन्चेव-अमेरिकी सम्बन्धों पर विवेचनात्मक दृष्टि (716)

17 शीतयुद्ध

721

(Cold War)

शीतयुद्ध क्या है (721), शीतयुद्ध के कारण (722), पश्चिम की पूर्व के विरुद्ध शिकायतें (722), पूर्व (रुम) की पश्चिम के विरुद्ध शिकायतें (725), शीतयुद्ध का इतिहास (1947-1982) (727), 1947 से 1953 तक शीतयुद्ध (727), 1953 से 1958 तक का शीतयुद्ध (729), 1958 से 1976 तक का शीतयुद्ध (731), 1977 से मार्च 1982 के मध्य तक शीतयुद्ध के उतार-चढ़ाव (735), शीतयुद्ध की शिथिलता के कारण (738),

शीतयुद्ध और देशों (739), देशों का शीतयुद्ध पर प्रभाव (741), सैद्धान्तिक संघर्ष बनाम शक्ति राजनीति (741)

18 पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन 744

(Rebuilding and Re-organisation of Western Europe)

शान्ति निर्माण की समस्या (745), शान्ति निर्माण में षडिन्दाजों और प्रारम्भिक कार्य (746), पाँच शान्ति सन्धियाँ (747), आस्ट्रिया के साथ सन्धि (748), जर्मनी के साथ सन्धि (748), जर्मनी के साथ सन्धि बातों (749), अधिक पुनरुद्धार और एकीकरण (750), बेनेलक्स (750), मार्शल योजना (751), यूरोपीय परिषद (753), सीमित क्षेत्रों में सहयोग (755), पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा (756), नाटो और धारणा सन्धि के देशों द्वारा विश्व शान्ति बातों की छोट में अपनी सामूहिक सैनिक शक्ति में वृद्धि और इस प्रकार निःसस्त्रीकरण की अय्यकता (760), यूरोपीय ससद, जून 1979 एवं यूरोप के एकीकरण की और कदम (761), अधिकार का प्रभाव (763), यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन (नवम्बर 1980) (764)

19 आणविक शस्त्रों का प्रभाव 766

(Impact of Nuclear Weapons)

आणविक शस्त्रों का प्रभाव (766), सम्भावित आणविक शक्तियों और प्रथम आणविक विस्फोटों की तिथियाँ (770), भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में और इसका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव (771), भारत की परमाणु नीति (773), भारत के निम्न परमाणु बम का प्रश्न देश की अस्मिता की रक्षा का प्रश्न है (774), परमाणु की राजनीति (776), परमाणु अस्त्रविहीन क्षेत्र आवश्यक (778), तथा अणु शस्त्रों के बल पर ही अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता राजनीति में स्थान सम्भव है (780), अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा धाज और बल (782), परमाणु अस्त्रों के विरोध में शान्ति का यूरोपीय मोर्चा (784), युद्ध की विभीषिका में आगन्तित यूरोपीय जनमत और सरकारों पर दबाव (785)

20 गूट-निरपेक्षता और बदलते प्रतिमान 789

(Non-Alignment and Changing Patterns)

गूट-निरपेक्षता का अर्थ और उसके तत्व (789), गूट-निरपेक्षता और तटस्थता (791), गूट-निरपेक्षता की प्रोत्साहन देने वाले कारक (792), सैनिक सन्धियों में आबद्ध होने के कारण (793),

गुट-निरपेक्षता की प्रेरण प्रक्रिया (794), निर्गुट प्रान्तीयता का विकास (796), गुट-निरपेक्षता की नीति, उसका विकास और प्रभाव (800), गुट-निरपेक्षता की प्रक्रिया, विभिन्न सम्मेलन (804), प्रथम शिखर सम्मेलन (बेलग्रेड) 1961 (804), द्वितीय शिखर सम्मेलन (वाटिका) 1964 (805), तृतीय शिखर सम्मेलन (मुंबई) 1970 (805), चौथे शिखर सम्मेलन (मस्को) 1972 (805), पंचम शिखर सम्मेलन (मस्को) 1973 (806), छठे शिखर सम्मेलन, 1974 (806), मार्च 1975 में हुआ सम्मेलन (806) अगस्त 1975 में लोमा सम्मेलन (807), गुट-निरपेक्ष देशों का मन्त्रिमण्डलीय सम्मेलन, जुलाई 1976 (808), कोन्फ्रेंस में गोपनीय निर्गुट शिखर सम्मेलन, अगस्त 1976 (808), गुट-निरपेक्ष सम्मेलन हुआ 1978 (810), बेलग्रेड गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जुलाई 1978 (811), कोन्फ्रेंस में गुट-निरपेक्ष समन्वय समूहों की बैठक, जून 1979 (813), गुट-निरपेक्ष सम्मेलन, हुआ (नवम्बर 1979) (813), विदेश मंत्रियों का नई दिल्ली सम्मेलन, फरवरी 1981 (815), एक गुट-निरपेक्ष देश के रूप में भारत (816), गुट-निरपेक्षता के बदलते हुए रूप (821), वर्तमान परिस्थितियों में गुट-निरपेक्षता का महत्व (822)

- 21 द्वि-ध्रुवीयता (द्वि-केन्द्रीयता) एवं बहु-केन्द्रीयता 827
(Bipolarity and Polycentrism)

बहुरी द्वि-ध्रुवीयता (827), शिथिल द्वि-ध्रुवीयता—बहु-केन्द्रीयता की ओर विकास (831)

- 22 अमेरिका, रूस और चीन के सम्बन्ध 838
(US, USSR and China Relations)

अमेरिका-रूस सम्बन्ध (838), अमेरिका-चीन सम्बन्ध (842), चीन-अमेरिका सम्बन्ध (1949-1968) : उपवादी नीति (843), चीन-अमेरिका सम्बन्ध (1969-1982) : तनाव-शान्ति की ओर प्रगति (848), सोवियत संघ और चीन के सम्बन्ध : चीन सोवियत संधि (851), रूस चीन में सहयोग का काल (852), रूस चीन में मतभेद और कटु वैमनस्य का काल (853), रूस चीन विवाद के मुख्य कारण (855), रूस चीन के समझौते प्रयास (859)

- 23 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रभाव 861
(UNO's Impact on International Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने की दृष्टि में संयुक्त राष्ट्रसंघ का स्वरूप (861), संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्था एक

नजर में (863), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से संघ के प्रांतों के अधिकार व कर्तव्य (864), महामभा (864), सुरक्षा परिषद् (867), सुरक्षा परिषद् द्वारा की गई कुछ बाध्यकारी (नैतिक) कार्यवाहियाँ (872), निषेधाधिकार की समस्या (874), निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क (876), निषेधाधिकार के पक्ष में तर्क (877), सुरक्षा परिषद् की भावी भूमिका (879), ग्याम परिषद् (880), अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (881), सचिवालय और महासचिव (882), शान्तिपूर्ण समाधान एवं प्रतिरोधात्मक प्रयत्न बल प्रयोग की प्रक्रिया (884), शान्तिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाएँ (884), प्रतिरोधात्मक प्रयत्न बल-प्रयोग की प्रक्रियाएँ (886), संयुक्त राष्ट्रसंघ की विश्व शान्ति सम्बन्धी भूमिका प्रयत्न संघ का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव (887), संयुक्त राष्ट्रसंघ की विभिन्न एजेंसियों और संस्थाएँ : गैर-राजनीतिक कार्य (900), संयुक्त राष्ट्रसंघ की दुर्बलताएँ (901), संघ की शक्तिशाली बनाने के सुझाव (905), मूल्यांकन (907)

24 वियतनाम की समस्या और पश्चिमी एशिया में समस्या-क्षेत्र 910
(The Problem of Vietnam and Problem Areas in West Asia)

वियतनाम की समस्या (910), वियतनाम का विभाजन : जेनेवा समझौता (911), युद्ध-विराम की असफलता और वियतनाम गृहयुद्ध (912), वियतनाम का एकीकरण और उसकी विदेश-नीति (913) अरब-इजरायल संघर्ष प्रयत्न पश्चिम एशिया की समस्या (913), अरब-इजरायल समस्या (1948-1967) (914), अरब इजरायल तनाव और शान्ति प्रयास (जुलाई, 1967-1972) (916) अरब इजरायल गृहयुद्ध (1973-1980) एवं अरब इजरायल विवाद 1981-1982 (921), ईराक-ईरान संघर्ष (924), ईराक ईरान संघर्ष का इतिहास (926)

25 पूर्वी यूरोप तथा हिन्द महासागर 929
(Eastern Europe and Indian Ocean)

पूर्वी यूरोप (929), हिन्द महासागर (934), भूगोल और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य (934), जलमार्ग एवं तटवर्ती देश (936), अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्पैठ का क्षेत्र, सैनिक महत्त्व एवं क्षेत्रीय सहयोग (937), हिन्द महासागर और बड़ी ताकतें तथा भारत की नीति (939), हिन्द महासागर में प्राणविक युद्ध का खतरा (940)

26 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ अन्य पहलु और नवीन घटना-धारा
(Some Other Aspects and New Developments of International
Politics)

944

- विशाली मामिला : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया विस्फोटक
केन्द्र (944), पश्चिमी जर्मनी-पोलैंड सम्झौता, मार्च 1977
(945), अफगानिस्तान में शांति (1979) : रुसी हस्तक्षेप
(946), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का नया गिनरा इस्लाम (947),
धर्म और राष्ट्रों की विवादता (948), वैचारिक आधार बिना
(949), सामूहिक प्रयास की महत्ता (949), मुस्लिम अल्पसंख्यकों
में बिना (950), मोरक्को के राजदूत का बहिष्कार (950), इस्लामी
विवादों की भावना (951), आतंकवाद (951), अन्तर्राष्ट्रीय
इस्लामी विवादता (952), इस्लामी देशों का अन्दर सम्मेलन
1979 : नए गन्दर्भ में (953), दिल्ली में राष्ट्रकुल का क्षेत्रीय
सम्मेलन (नितम्बर 1980) (955), घाटेवा शिखर सम्मेलन
(जुलाई 1981) (958), घाटेगुप्ता : 349 मानव बाध स्वाधीन
(961), राष्ट्रकुल सम्मेलन, नितम्बर-अक्तूबर 1981 (961),
मेनबोर्न सम्मेलन में भारत का बर्चस्व (964), बंनकुन शिखर
सम्मेलन (अक्तूबर 1981) (966), बंनकुन के अन्दर (969),
भारत अमेरिका का सम्बन्ध : सुधार के प्रयास (971), अमेरिका
और मध्य अमेरिकी राज्य : अन्तर्मुखी निर्णायक मध्य के
क्षेत्र में (974), नई चेतना जीवन मरण का मध्य (976),
मित्र भी समर्थक नहीं (978)

जनवरी 1977 से अप्रैल 1982 तक की महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय
घटनाओं की भूतक

980

प्रश्नावली (University Questions)

998

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का परिचय (An Introduction to International Politics and International Political System)

“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भाँति शक्ति के लिए संघर्ष है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्तिम उद्देश्य कुछ भी हो, उसके पीछे शक्ति प्राप्त करना ही सदैव अन्तिम उद्देश्य होता है।”

—हंस जे. मॉगेंथो

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ कभी यूरोप की राजनीति से ही लिया जाता था। उस समय लगभग समूचे विश्व में यूरोपीय राष्ट्रों की राजनीति ही प्रभावी थी और एशिया तथा अफ्रीका में अपने प्राथिक एवं औपनिवेशिक विस्तार के लिए यूरोप के राज्य युद्धों तथा कूटनीतिक दाव-पेचों में संलग्न थे। उनकी शक्ति-सम्पत्ता, औद्योगिक प्रगति, विकसित तकनीक और प्रसारवादी महत्वाकांक्षामें से पूर्ण राजनीति की तुलना में विश्व के अन्य देशों की राजनीति बहुत-कुछ भ्रान्त और स्थानीय थी। लेकिन कालान्तर में इतिहास की घाटा पलटी और प्रथम महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बदला। दो महायुद्धों के बीच अधिनाश विश्व के एक बड़े भाग में आर्थिक सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में शान्तिकारी परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने देशों की आन्तरिक और बाह्य राजनीति को आधारभूत रूप में प्रभावित किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद अणु-शक्ति ने राष्ट्रों की राजनीति और सामरिक नीति को एक नया मोड़ दिया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध जबर्दस्त प्रतिप्रिया हुई। एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों का प्रभुत्व एवं प्रभाव तेजी से बढ़ा जिसकी उपेक्षा करना किसी भी महाशक्ति के लिए आत्मघाती हो सकता था। इन सब घटनाओं तथा क्रिया-प्रतिक्रियाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदल दिया तथा उसके आकार और आयामों को सच्चे अर्थों में ‘अन्तर्राष्ट्रीय’ बना दिया। इसके फलस्वरूप आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल यूरोप की राजनीति मानने के दिन समाप्त हो चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व आज निर्विवाद है और एक रबतन्त्र विषय के रूप में उसका महत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतन्त्र विषय के रूप में (International Politics as an Independent Discipline)

द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का कतेवर बड़ा घोर उमके अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा। इसमें यह विवाद उठा कि इसे एक स्वतन्त्र अध्ययन-शास्त्र के रूप में मान्यता दी जाए अथवा नहीं। मैनिंग, स्विगीराइट, हापसन जैसे विद्वान् इसे एक स्वतन्त्र विषय अथवा शास्त्र मानने के पक्ष में हैं। मैनिंग (A. W. Manning) का प्रमुख तर्क यह है कि "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक बृहत् विषय तथा विशाल सामाजिक विश्व (Social Cosmology) का अंग है।" इस सम्बन्ध में वह तीन बातें बतलाते हैं—(i) सामाजिक विश्व के अन्तर्गत सम्पूर्ण सगर में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक जाल है, अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वतन्त्र अध्ययन आवश्यक है। (ii) इसके लिए एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण (Universalistic Angle) आवश्यक है और यह दृष्टिकोण तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को हम एक स्वतन्त्र विषय न मान लें। अन्तर्राष्ट्रीय रण-मंच पर जो भी घटित घटनाएँ घटित होती हैं, उन्हें समझने, सही और समुचित गन्धर्भ में रगने तथा उनकी दिशाओं को जानने का यही सही एवं सर्वोत्तम तरीका है। (iii) यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की घटनाओं के सही स्वरूप को न समझ सकें अथवा उनकी दिशाओं का आभास न पा सकें तथा समस्याओं के समाधान की दिशा में समुचित रूप से विचार न कर सकें तो हमारे अध्ययन का कोई लाभ नहीं होगा।¹ स्विगी राइट (Quincy Wright) ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वतन्त्र शास्त्र मानने के सम्बन्ध में प्रमुख तर्क यह दिया है कि "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय आज हमारे विभिन्न विषयों से लाभ उठाकर समन्वयात्मक ढंग से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होना जा रहा है। उन्होंने ऐसे आठ विषय भी गिनाए हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन की भूल सामग्री हैं।"² हापसन ने इस विषय के स्वतन्त्र अस्तित्व के सम्बन्ध में एक भिन्न तर्क देते हुए कहा है कि ये विश्व-राज्य रूपी इकाइयों में प्रगाढ़ सम्बन्ध हैं जो इन इकाइयों के अथवा राज्यों के बाह्य आचरणों के और नीतियों के परिणाम हैं। इस प्रकार हापसन यह प्रतिस्थापित करना चाहते हैं कि हम राज्यों के आन्तरिक मामलों का विवेकपूर्ण अध्ययन तभी कर सकते हैं जब उनकी बाह्य क्रियाओं का विशद्, गहन और समुचित अध्ययन करें। स्पष्ट है कि इन अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतन्त्र विषय के रूप में उतना ही मान्य है जितना कि राजनीतिशास्त्र। आखिर राष्ट्रीय राजनीति को भी हम सही ढंग में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्दर्भ में समझ सकते हैं।

कैपर जॉनसन (Capper Johnson) ने लिखा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को हम इतिहास अथवा राज-शास्त्र का अंग नहीं मान सकते क्योंकि इसका क्षेत्र उनसे

1 A W Manning (Ed) : The University Teaching of Social Sciences-International Relations (UNESCO 1254), p. 10.

2 Quincy Wright : The Study of International Relations, pp. 23-24

कही अधिक व्यापक है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिशास्त्र जो सामग्री एकत्रित करता है वह दूसरे शास्त्रों की सामग्री से स्पष्टतः भिन्न है। साथ ही इस सामग्री को ममन्वित करने की उसकी पद्धति भी निराली है। अतः सामाजिक विज्ञानों में उसे एक स्वतन्त्र शास्त्र मानना उचित है।¹ जे. डब्ल्यू. बर्टन (J. W. Burton) ने अपना निष्कर्ष दिया है कि "अन्ततः इसका (अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का) एक अपना अन्तर्जातीय ढाँचा विकसित होगा जो राज्यों के पारस्परिक व्यवहार के विविध पक्षों के बारे में किए गए विशिष्ट अध्ययनों से गठित होगा और तब उसे अन्यान्य सामाजिक विज्ञानों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।"²

पी. डी. मर्चेंट, रॉबर्ट सीमिंग, काप्लान, जॉर्ज केनन आदि ऐसे विद्वान् भी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतन्त्र विषय के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। विरोध में पहला तर्क यह दिया जाता है कि किसी भी शास्त्र के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है—निश्चित अध्ययन-सामग्री, स्पष्ट विधेयता-पद्धति और सर्वमान्य सिद्धान्त-निकाय, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कार्य राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों और उनके प्रेरक तत्वों अर्थात् राज्यों की नीति-निर्धारण-प्रक्रिया का सम्पूर्ण अध्ययन करना है और यह अध्ययन वह स्वतन्त्र रूप से नहीं कर सकता, अपितु उसे राजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। इन स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतन्त्र शास्त्र का दर्जा देना उपयुक्त नहीं है। काप्लान इसे राजशास्त्र अथवा राजनीतिशास्त्र (Political Science) के विभाग के रूप में मानने के पक्ष में है और जॉर्ज केनन का भी बहुत-कुछ यही अभिमत है। अपने पक्ष में इन विद्वानों का तर्क है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अभी तक राजनीतिशास्त्र का अंग माना जाना रहा है। राष्ट्र मूलतः एक राजनीतिक इकाई है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व के राष्ट्रों के राजनीतिक सम्बन्धों, राजनय, शक्ति के लिए संघर्ष आदि से सम्बद्ध है, अतः इसे राजनीतिशास्त्र का अंग मानते रहना ही उचित होगा।

चाहे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतन्त्र विषय स्वीकार करने के विचार का विरोध किया जाए, किन्तु दो बातें निश्चित रूप से स्पष्ट हैं—पहली बात तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की अध्ययन-सामग्री निरन्तर बढ़ती जा रही है और आज इसका ताना-बाना इतना जटिल, बहुगुणी और विशिष्ट बनता जा रहा है कि यह विषय किसी अन्य शास्त्र जैसे राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय कानून या अर्थशास्त्र के अन्तर्गत नहीं रह सकता। दूसरी बात यह है कि आज भले ही इसके स्वतन्त्र रूप पर सन्देह किया जाए, लेकिन कल ऐसा नहीं रहेगा। इस मान्यता की पुष्टि में विवेक कारण हैं। अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए सिद्धान्तों (Theories) का विवेचन होने लगा है। 1947 में प्रकाशित अपने ग्रन्थ 'राष्ट्रों के

1 Karlin M. Copper Johnson : The Discipline of International Affairs, pp. 6-7.

2 J. W. Burton : International Relations, p. 13.

4 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

मध्य राजनीति' (Politics Among Nations) में हेंम जे. मॉर्गेंथो ने पहली बार एक व्यवस्थित सिद्धान्त का निरूपण किया जो 'व्यावर्तवादी सिद्धान्त' (Realist Theory) कहलाता है। इसके बाद से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए और भी अनेक सिद्धान्तों का प्राणित रूप से निरूपण किया जा चुका है और इस बात की प्रबल सम्भावना है कि शीघ्र ही सामान्य सिद्धान्तों का गठन किया जा सकेगा। इस विषय के अध्ययन में व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में जो विभिन्न दृष्टिकोण अथवा ढंग (Approaches) विकसित हो रहे हैं वे उत्साहवर्धक चिह्न हैं और जिस दिन सिद्धान्तों में स्थिरता आ जाएगी उग दिन इसके स्वतन्त्र विषय होने पर कोई सन्देह नहीं रहेगा। निश्चित अध्ययन-नामप्री, जिसके विस्तारण द्वारा सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया जा सकता है, उपलब्ध है, स्पष्ट संवेपणा-पद्धति का अस्तित्व किसी से छिपा नहीं है, केवल एक सर्वमान्य सिद्धान्त अथवा सिद्धान्त-निष्ठा का आविर्भाव बाकी है। इस दिशा में भी प्रमाण काफी प्रगति पर है और समस्या का समाधान निश्चित रूप में निश्चि भविष्य में ही हो जाने की सम्भावना है। विभिन्न राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए पृथक् विभागों अथवा मस्थाओं की व्यवस्था कायम की जा चुकी है। विरासतीय देश तक इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरणार्थ, भारत में 'Indian School of International Studies' इसी एक स्वतन्त्र विषय के रूप में मान्यता दिलाने की ओर गम्भीर प्रयास है तथा विश्वविद्यालयों में इस पर पृथक् रूप से परीक्षा-पत्र दिए जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विकास के चार स्तर (Four Stages of Development of the Study of International Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वतन्त्र शास्त्र मानने की प्राधुनिक धारणा पर विद्वान् एकाएक ही नहीं पहुँचे हैं। इस विषय के कतिपय प्रमुख अध्ययन-पोषण रहे हैं और विकास की महत्वपूर्ण मजिदों को पार करके यह अपनी प्राधुनिक अवस्था में पहुँचा है। कॅनेथ थॉम्पसन ने इस विषय के अध्ययन के चार मुख्य स्तर स्वीकार किए हैं।¹

प्रथम स्तर (The First Stage)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का प्रथम चरण प्रथम महायुद्ध के अन्त तक रहा जिसमें कूटनीतिक इतिहासज्ञों का एकाधिकार छाया रहा और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की पढ़ाते समय समकालीन राजनीतिक घटनाओं की गहन ज्ञान की अपेक्षा कर भूतकालीन राजनीतिक और कूटनीतिक इतिहास का परिचय देना ही पर्याप्त समझा गया। इतिहास से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल कर उनसे समकालीन

1 *Kenneth W. Thompson : The Study of International Politics—A Survey of Trends and Developments—Review of Politics* (14 Oct., 1952), pp. 433-67.

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की सगति बँटाने का कोई प्रयाग नहीं किया गया। कूटनीतिक इतिहासज्ञों ने तथ्यों के अपने वर्णनात्मक अध्ययन से कोई सारंभौमिक निद्धान्त निकालने की चेष्टा नहीं की। इस प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि उनके अध्ययन और अध्यापन से विगत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की सध्यात्मक जानकारी तो समुचित रूप में मिली, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के तत्कालीन स्वरूप अथवा उनकी भावी दिशा को समझने में कोई सहायता नहीं मिल सकी। इस एकांगी ऐतिहासिक अध्ययन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के निद्धान्त-पक्ष का विकास नहीं हो पाया। अध्ययन की यह एकांगी परम्परा बहुत पुरानी और अपूर्ण होती हुए भी एशिया तथा अफ्रीका के कुछ अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में जीवित है। उदाहरणार्थ, कुछ वर्षों पूर्व तक अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में यही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति प्रचलित थी।

द्वितीय स्तर (The Second Stage)

महायुद्धकालीन अनुभवों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को एक नया मोड़ दिया। महायुद्ध के बाद 1919 में वेमस विश्वविद्यालय में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग खुला और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में समकालीन घटनाओं और समस्याओं (Current Events and Problems) के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। यद्यपि यह कदम कूटनीतिक ऐतिहासिक अध्ययन के एक अभाव की पूर्ति था तथापि यह भी एकांगी ही था। इस नवीन दृष्टिकोण में भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का समुचित अध्ययन सम्भव नहीं था क्योंकि विगत अथवा भूतकालीन घटनाओं की उपेक्षा करते हुए केवल वर्तमान के अध्ययन पर ही अधिकाधिक ध्यान था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के प्रथम चरण में विद्वान् केवल विगत कूटनीतिक इतिहास के अध्ययन से ही सन्तुष्ट हो जाते थे और वर्तमान से उसका सम्बन्ध स्थापित नहीं करते थे, किन्तु अब विद्वान् केवल वर्तमान के अध्ययन में ही इतने लीन होने लगे थे कि उन्होंने भूतकाल के इतिहास के अध्ययन की ओर अप्रत्याशित बेरखी अपनाई। इस एकांगी दृष्टिकोण का भी यह स्वाभाविक परिणाम निकला कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन-क्षेत्र में कोई समुचित तैदान्तिक अथवा विधिज्ञात्वीय आधारशिला नहीं रखी जा सकी और ऐसे प्रयासों की स्थापना नहीं हो सकी जिनके द्वारा इतिहास की सम्पूर्णता के सन्दर्भ में वर्तमान घटनाओं के महत्व को समझा जा सकता और अन्तर्राष्ट्रीय आचरण की भावी दिशा का संकेत प्राप्त हो सकता। इस बात की उपेक्षा ही रही कि वास्तव में भूत और वर्तमान की युक्तियुक्त सम्बन्ध-स्थापना द्वारा ही किसी विषय का सम्यक् विकास सम्भव है।

तृतीय स्तर (The Third Stage)

द्वितीय स्तर के विकास के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का तृतीय स्तर भी आरम्भ हुआ और ये दोनों ही स्तर दोनों महायुद्धों के बीच की अवधि में प्रभावशाली रहे तथा द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में भी ये प्रचलित नहीं

है। इस तृतीय स्तर में बानून और संगठन के माध्यम में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संस्थानीकरण (Institutionalization of International Relations) पर ध्यान दिया जाने लगा। प्रथम महायुद्ध-काल के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों ने राष्ट्रों के लिए नवीन सन्देश, नवीन भाषा और भावी सम्बन्धों की सम्भावित प्राप्तिशक्ती प्रस्तुत की और पैरिस-सम्मेलन में एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय समस्या 'राष्ट्रसंघ' का जन्म हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक नए परिवेश और नए स्वरूप में सामने आया। इन सब ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादिता का पुट दिया जिनके फलस्वरूप इसका अध्ययन आदर्शानुसृत हो गया।

अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन इस विश्वास में प्रेरित हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज ऐसी समस्याओं का निर्माण कर मानने में समर्थ होगा जिनके द्वारा सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ वैधानिक एवं शान्तिपूर्ण ढंग में सुलझाई जा सकेंगी। अतः अब उन उद्देश्यों और मूल्यों की खोज की जाने लगी जिन्हें प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रयत्नशील होना चाहिए। साथ ही ऐसी समस्याओं के निर्माण की कल्पनाएँ सजोई जाने लगी जिनके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इन उद्देश्यों और मूल्यों को प्राप्त कर सके। आशावाद की इस नवीन लहर ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में आदर्शवादी और सुधारवादी दृष्टिकोण का गूँथपात किया। अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का अर्थ था राष्ट्रसंघ का अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय बानून का अध्ययन, शान्ति कायम रखने के मार्ग का अध्ययन आदि। भावात्मक और काल्पनिक सुधारवाद का तत्त्व इतना प्रबल हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्बन्धित विद्वान् एत आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण की कल्पना के रंगीन स्वप्नों में ली गए और अन्तर्राष्ट्रीय जगत की वास्तविकताओं तथा कटु सत्यों की उपेक्षा कर आदर्शवाद और सुधारवाद के जोश में सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान केवल बानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के माध्यम से सम्भव मानने लगे। हंस मॉर्गेंथौ ने ठीक ही लिखा है कि दो महायुद्धों के बीच की इस अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों की प्रवृत्ति "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति को समझने की नहीं रही बल्कि उन बानूनी समस्याओं और संगठनों के विकास की रही जो तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर छा सकें।"¹ विद्वान् इस दिशा में इतने दूर गए कि मानों अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और बानून की स्थापना मात्र से अन्तर्राष्ट्रीय जगत की समस्याएँ हल हो जाएँगी।

चतुर्थ और वर्तमान स्तर

(The Fourth and the Modern Stage)

इस प्रकार 1919 से लेकर द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विकास के तीन मुख्य स्तर रहे—बूटनीयक इतिहास; अन्तर्राष्ट्रीय बानून और संगठन एवं सामयिक घटनाओं के अध्ययन पर एकाग्रता;

1 Hans J. Morgenthau : The Intellectual and Political Functions of a Theory of International Relations, in Horrace V. Harrison, ed., The Role of Theory in International Relations, p. 107.

तथा राजनीतिक सुधार व आदर्शवाद। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने जो पलटा था, राष्ट्रमण की प्रभुत्वता ने जो आघात पहुँचाया और सामूहिक सुरक्षा-प्रणाली की अभावहारिकता ने लोगों की ऊँची आशाओं पर जो तुफानपात किया, उससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी प्रवृत्ति को बल मिला। वास्तव में इस प्रवृत्ति के शक्तिशाली प्रकुर तो 1930 की महान् आर्थिक मन्दी के बाद से ही प्रस्फुटित हुए और एक के बाद एक तेज़ी से घटने वाली राजनीतिक और सैनिक घटनाओं ने इस प्रवृत्ति की जड़ें जमा दी। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद घोषित आदर्शवाद और काल्पनिक सुधारवाद अतीत की चीज बन कर रह गई।

विकास के इस नये और वर्तमान चरण में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में उन शक्तियों और प्रभावों पर बल दिया जाने लगा जिनसे राष्ट्रों के व्यवहारों का निरूपण होता है। यह अनुभव हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ एक ढग से घटित होती हैं और आदर्श के धरातल से बहुत कुछ परे रहती हैं। यह सुस्पष्ट हो गया कि 'शक्ति' (Power) की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र में सबसे अधिक है। शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय जगत का सबसे बड़ा यथार्थ प्रतीक होने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का 'यथार्थवादी सिद्धान्त' भी प्रतिपादित हुआ। अब इन बातों का अध्ययन होने लगा कि विदेश नीतियों को नियंत्रित करने और संचालित करने वाले कौन-कौन से तत्व हैं, विदेश नीति किम ढग से और कैसे कार्यान्वित होती है, अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान कैसे किया जाए, आदि। पहले के संस्थापरक दृष्टिकोण (Institutional Approach or System-Oriented View) के स्थान पर अब इकाईपरक दृष्टिकोण (Entity Oriented View) अपनाया जाने लगा जिसके अनुसार विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को स्वतन्त्र इकाई मानकर उनके गठन, कार्य और लक्ष्यों का अध्ययन करने की प्रवृत्ति विकसित हुई। सम्पूर्ण विश्व को एक अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक इकाई और विभिन्न राष्ट्रों को उसका घन मानकर दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करने की आदर्शवादी और यथार्थवादी प्रवृत्ति के दिन खद गए। दोनों महायुद्धों के बीच के काल में जहाँ राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का केन्द्र था वहाँ अब विश्व-राजनीति के ढाँचे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन होने लगा। आज संयुक्त राष्ट्र-संघ के कार्यों और उद्देश्यों का अध्ययन सांविधानिक सन्दर्भ की अपेक्षा राजनीतिक सन्दर्भ में अधिक किया जाता है। विश्व-समस्याओं के अध्ययन का उद्देश्य अब उनकी प्रशंसा या निन्दा करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और समाधान के सन्तुलित और समुचित साधन खोजना है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन-क्षेत्र में आज मुख्य विषय सैद्धान्तिक खोजबीन का है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को समझने के लिए सैद्धान्तिक योगदान बहुत लम्बे असे से अप्रभावशाली रहा है। किसी राइट ने ठीक ही लिखा है कि जो सिद्धान्त निरूपित किए गए उनका मुख्य उद्देश्य सैनिक व्यूह रचनाकारों, कूटनीतिज्ञों, न्यायविदों, साम्राज्यवादियों, मानसशास्त्रियों, प्राविधिज्ञों, अर्थशास्त्रियों और वाणिज्यों जैसे वर्गों या समूहों के लिए उपयोगी होना था। उन

गिद्धान्तों में गिद्धान्तवादियों के गरीब हितों का ही प्रतिबिम्ब भलवता था, उनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सम्पूर्ण क्षेत्र में सम्बन्ध नहीं था। लेकिन द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के वैधानिक गिद्धान्तों के विराग के प्रगमनीय प्रयाग हुए हैं और यद्यपि अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का कोई सामान्य गिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया जा सका है तथापि जो कुछ भी प्रगति इस दिशा में की गई है वह निःसन्देह उत्साहपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए उपयोगी गिद्धान्तों का विवेचन होने लगा है। उदाहरण के लिए, हेग मॉमेंटो द्वारा प्रतिपादित 'यथार्थवादी गिद्धान्त' इस क्षेत्र में एक आन्ति का चोतर है और जिस सम्भीरता में विभिन्न शांतिर गिद्धान्तों का निरूपण होता जा रहा है उनमें यह सुनिश्चित है कि जो प्र ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन-क्षेत्र में एक सामान्य गिद्धान्त (A General Theory) का गठन भी किया जा सकेगा।

गर्वाधर महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन अपने स्वरूप और विषय-मामयों की दृष्टि में आन्तिकारी रूप में परिवर्तित हो गया है। इस परिवर्तन में अनेक महत्वपूर्ण कारकों का योग रहा है। अणुशक्ति के विराग, तकनीकी प्रगति, उपनिवेशवाद की नेत्री में समाप्ति, नए राष्ट्रों का उदय, पुराने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की समाप्ति और उनका नवीनीकरण, नए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का आविर्भाव, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता और जनमन की बढ़ती हुई भूमिका और इन सबमें परे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के ज्ञान-क्षेत्र में एक सैद्धांतिक व्यवस्था के निर्माण की इच्छा आदि तत्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन-दृष्टिकोण में युगान्तरकारी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। इसका अभिप्राय है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन इन और इमी प्रकार के अन्य तत्वों के मन्दर्न में करना होगा। दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप का अध्ययन तब तक एकांगी और अपूर्ण रहेगा जब तक हम बीमयी शताब्दी के सामाजिक स्वरूप (Sociological Nature) के प्रागणिक अध्ययन को साथ लेकर न चलें।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान अध्ययन में यह भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है कि अब आदगंवादी यथवा यथार्थवादी दृष्टिकोणों से बंधकर चलना उपयुक्त नहीं समझा जाता। आज का अध्ययन किसी पूर्वकालिक अन्य अध्ययन की अपेक्षा अधिक मनुजित दृष्टि लिए हुए है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की वर्तमान पद्धति वैज्ञानिक एवं तटस्थ विरलेपरण की है यद्यपि उसका अन्तिम लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय जगत में पारम्परिक सहभाव और आन्ति की अभिवृद्धि ही है। यही वैज्ञानिक तटस्थता का प्रयोग अपने कठोर अर्थों में नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के समान निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना सम्भव नहीं है। सम्भवत इमीलिए कुछ विद्वानों ने इस प्रवृत्ति को 'आदर्शोन्मुख यथार्थवाद' कहना अधिक उपयुक्त समझा है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की इन वर्तमान प्रवृत्तियों के विकास का आशय यह नहीं है कि द्वितीय महायुद्ध में पहले की प्रवृत्तियों का कोई महत्व नहीं

रहा है। हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि जब तक हम 1945 से पूर्व की इस शताब्दी की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को नहीं समझेंगे तब तक 1945 के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप का भली प्रकार अध्ययन नहीं कर सकते। घटीत को पूरी तरह भुलाकर नवीन को पूरी तरह अपना लेने का दृष्टिकोण एकांगी और खतरनाक होगा। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान स्वरूप में दिखाई देने वाले परिवर्तन कोई 'सम्पूर्ण परिवर्तन' (Total Changes) नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने जहाँ कुछ पुरातन बातों को अपना रखा है, वहाँ बहुत से पुराने धोरों को तोड़ कर कुछ सर्वथा नवीन बातों को अपना लिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र

(Meaning, Nature and Scope of International Politics)

अर्थ एवं स्वरूप (Meaning and Nature)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को भली प्रकार समझने की दृष्टि से उपयुक्त होगा कि हम पहले 'राजनीति' (Politics) शब्द के अर्थ को सकेत रूप में जान लें। राजनीति का स्वरूप चाहे परेलू हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, उसमें प्रत्येक बात इस तथ्य में प्रकट होती है कि लोगों की अपनी-अपनी आवश्यकताएँ और इच्छाएँ हैं। इन आवश्यकताओं और इच्छाओं को सन्तुष्ट करने के प्रयागों के फलस्वरूप लोगों में सम्पर्क स्थापित होता है और इस सम्पर्क के कारण अन्तर्गतवा समूहों या वर्गों (Groups) का निर्माण होता है। किसी एक समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं और इच्छाओं में सामंतीर पर घति निकटना हो सकती है, किन्तु विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं और इच्छाओं का परस्पर भिन्न होना स्वाभाविक है। ये समूह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लीन होते हैं और अलग-अलग नीतियाँ अपनाते हैं। इस प्रकार राजनीति का उदय विभिन्न समूहों के अस्तित्व और उनके बीच पाई जाने वाली असहमतियों तथा लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को अधिकाधिक सन्तुष्ट करने के लिए विभिन्न सम्बन्धों के निर्माण के प्रयामों में होता है। इसी प्रक्रिया अथवा क्रिया-अनिक्रिया को ध्यान में रखते हुए किचरी राइट ने राजनीति को एक ऐसी 'कला' माना है "जिसके द्वारा बड़े गुटों अथवा समूहों को प्रभावित, छलबोजित या नियन्त्रित करके कोई समूह दूसरे समूहों के विरोध के बावजूद अपना स्वार्थ सिद्ध करता है।"¹

स्पष्ट है कि राजनीति के लिए तीन बातें अनिवार्य हैं—समूहों का अस्तित्व, समूहों के बीच असहमति और उनमें से कुछ का अपने हित साधन के लिए दूसरों को प्रभावित या नियन्त्रित करने का प्रयत्न। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीति समूहों, असहमति और सामूहिक कार्यों की घटना अथवा क्रिया है। पूर्ण असहमति (Complete Disagreement) तथा पूर्ण सहमति (Complete

Agreement) इन दोनों ही दशाओं में राजनीति का अस्तित्व सम्भव नहीं है। किन्तु इस प्रकार की स्थिति का उपस्थित होना भी असम्भव प्रायः ही है क्योंकि समूहों के परस्पर विरोधी स्वार्थों में टकराहट और उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए जोड़-तोड़ अवश्यम्भावी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शेल्डन वोलिन (Sheldon S. Volin) ने राजनीति को हमारे उन अनवरत प्रयासों की प्रक्रिया माना है जिनका उद्देश्य दूसरों के साथ ऐसे सम्बन्धों की स्थापना करना हो जो हमारे हित में सर्वाधिक लाभकारी गिड़े हो सकें।¹ इस प्रक्रिया में संघर्ष (Conflict) स्वतः निहित है जो राजनीति का मूल है। यह ध्यान रहे कि संघर्ष (Conflict) और विवाद (Disputes) एक नहीं है। संघर्ष राजनीति की प्रक्रिया में निरन्तर बने रहने वाली अवस्था है जबकि विवाद कुछ विशेष मामलों के सम्बन्ध में उठते हैं और शान्त हो जाते हैं। संघर्ष प्रभूत है जबकि विवाद उस संघर्ष का ठोस मूर्त रूप। चूँकि समूहों की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ असीमित होती हैं तथा उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं, अतः उन इच्छाओं और आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के प्रयासों में गुटों द्वारा अपना पक्ष प्रभावित या नियन्त्रित करने की जोड़-तोड़ चलती रहती है और इस प्रकार संघर्ष की प्रभूत स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। उसी मात्रा में अवश्य ही समयानुसार अन्तर हो सकता है। संघर्ष की यह स्थिति शक्ति (Power) की भूख बढ़ाती है। ऐसे माँगों के शब्दों में, "दूसरे गुटों या वर्गों के क्रिया-कलापों अथवा नीतियों को प्रभावित या नियन्त्रित कर सके की क्षमता का नाम 'शक्ति' (Power) है"; और शक्ति-प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष (Conflict) ही राजनीति का मूल है। वस्तुतः यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिससे शक्ति का अर्जन, रक्षण, प्रयोग और संचर्जन होता है।

'राजनीति' शब्द के अभिप्राय को सचेत रूप में समझ लेने के उपरान्त अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझना अति सुगम है। विश्व-राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों की राजनीति ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति है। दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हित-साधन के लिए आपसी सम्बन्धों में संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसी का अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में राष्ट्र समूह (Groups) हैं, उनकी आवश्यकताएँ और इच्छाएँ राष्ट्रीय हित (National Interests) हैं और राष्ट्रों या हितों के बीच असहमति ही संघर्ष (Conflict) है, किन्तु शक्ति का तत्व (Element of Powers) वही है। राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों में संघर्ष का उद्देश्य भी राष्ट्रीय क्षेत्र के समान ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी दूसरों की तुलना में अधिक लाभकारी स्थिति प्राप्त करना होता है। अपने पक्ष में दूसरे राष्ट्रों के क्रिया-कलापों या नीतियों को प्रभावित, नियन्त्रित अथवा छलधोखा करने की क्षमता का विकास करने के लिए विश्व के

1 Sheldon S. Volin : Politics and Vision—Continuity and Innovation in Western Political Thought, p. 11.

राष्ट्र अनवरत जोड़-तोड़ में लगे रहते हैं, संघर्ष की स्थिति में उलझे रहते हैं। सारांश में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तीन तत्व आवश्यक हैं—राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति (National Interest, Conflict and Power)। राष्ट्रीय हित उद्देश्य है, संघर्ष स्थिति विशेष है और शक्ति उद्देश्य-प्राप्ति का साधन है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष (Conflict) विशेष महत्वपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय समाज से संघर्ष की स्थिति का लोप नहीं हो सकता, अतः शक्ति के माध्यम से सामञ्जस्य की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। संघर्ष की निरन्तर उपस्थिति का भाग्य यह नहीं है कि विश्व के राष्ट्र सदैव एक दूसरे से टकराव करते हैं। जिन राष्ट्रों के हित परस्पर समान होते हैं उनमें सहयोग भी होता है। दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों सन्निहित हैं। पर सहयोग भी अन्तिम रूप में संघर्ष का ही परिणाम है, क्योंकि एक तो जिन राष्ट्रों के हित परस्पर समान होते हैं वे भाग्य में सहयोग इसीलिए करते हैं कि दूसरे राष्ट्रों के संघर्ष पर विजय पा सकें और दूसरे, सहयोग की भाकांक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्वभावतः संपरंपूर्ण होते हैं। कहने का भाग्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्य किसी भी राजनीति की तरह, अपनी प्रकृति में एक निरन्तर गतिमान घटना अथवा क्रिया है—ऐसी क्रिया जिसमें संघर्ष को केन्द्रीय स्थान प्राप्त है और इसके माध्यम से अथवा इससे उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से शक्ति (Power) के भर्जन, रक्षण, प्रयोग और सवर्द्धन का प्रयास किया जाता है।

क्षेत्र (Scope)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र को विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों के अनुसार विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। इसके अर्थ और स्वरूप में हम इसके क्षेत्र का आभास मिल चुका है। अधिक स्पष्टता के लिए उचित होगा कि हम पहले कुछ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं को जान लें और फिर विषय-क्षेत्र की व्याख्या करें। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ ये हैं—

हंस मॉन्टेन्थो—“राष्ट्रों के मध्य शक्ति (Power) के लिए संघर्ष तथा उभरा प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है।”

केलिक्स ग्रस—“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव के राष्ट्रों की विदेश-नीतियों का अध्ययन ही है।”

रम्राउट—“स्वतन्त्र राजनीतिक समुदायों (अर्थात् राज्यों) के अपने-अपने उद्देश्यों अथवा हितों के आपसी विरोध-प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया-प्रतिक्रियाओं और सम्बन्धों का अध्ययन ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति है।”

मॉन्पेसन—“राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ उनके पारस्परिक सम्बन्धों को गुंथाने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं।”

हार्डमेन—“अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अभिप्राय उन प्रक्रियाओं के अध्ययन से है जिनके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का सामञ्जस्य अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों के साथ बँटाते हैं।”

पेंडेलकोइ एवं लिफन—“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति राजमत्ताओं के बदलते सम्बन्धों के मन्दमं में राज्यों की नीतियों की अन्त प्रिया है।”

यर्टन—“अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में सामान्य बातों के अनिश्चित वे सभी पटनाएँ और परिस्थितियाँ भी सम्मिलित हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है।”

हेंग मॉर्गेंथो का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ‘शक्ति’ का तत्व प्रधान है। प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के लिए प्रयत्न करता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ‘शक्ति’ की राजनीति है। न केवल राष्ट्रीय हित को बढ़ाने, प्राप्त करने अथवा नार्थान्वित करने के लिए अतितु अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच पर अपनी भूमिका निभाने के लिए यह क्षमता अर्थात् ‘शक्ति’ अनिवार्य है। मॉर्गेंथो के अनुसार, राष्ट्रों के बीच सभी सम्बन्ध राजनीतिक नहीं होते क्योंकि राष्ट्र सामान्यतः अनेक ऐसे कार्य भी करते हैं जिनका शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं होता और न ही उनमें राष्ट्र की शक्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रों के अनेक कानूनी, आर्थिक, मानवीय और सांस्कृतिक कार्य-जलाशो को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत नहीं गिना जा सकता। मॉर्गेंथो का निष्कर्ष है कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतियों के समान, शक्ति के लिए मध्यम का ही नाम है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे अन्य कुछ भी उद्देश्य हो पर उमका तात्त्विक उद्देश्य मंदव शक्ति ही रहता है।”¹ मॉर्गेंथो के तर्क में बल है तथापि यह नहीं भूलना चाहिए कि ‘शक्ति’ एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। राष्ट्र केवल ‘शक्ति’ के लिए ही कोई राजनीति संचालित नहीं करते। साथ ही यह तथ्य भी विस्मृत नहीं किया जा सकता कि ‘शक्ति’ चाहे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का चिन्ता ही प्रमुख तत्व हो, इसकी सीमाएँ हैं।² यदि शक्ति की सीमाओं को मुला कर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाएगा, तो न तो वह अध्ययन सही होगा और न ही उसके आधार पर हम सही नतीजे पर पहुँच सकेंगे।

फेलिक्स ग्रॉस, रसेल फाइफील्ड आदि विद्वानों ने राष्ट्रों की विदेश-नीतियों के अध्ययन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति माना है।³ यह तर्क दिया गया है कि जब तक हम राष्ट्रों की विदेश-नीतियों को नहीं समझ लेंगे तब तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को ही नहीं समझ सकते। इन विद्वानों ने दोनों के बीच इतना अनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर दिया है कि एक का अध्ययन दूसरे का अध्ययन बन गया है, एक को दूसरे का

1 Hans J Morgenthau : Politics Among Nations, p. 27.

2 B Russel : A New Social Analysis, 1934.

3 Feliks Gross : Foreign Policy Analysis, pp 2, 24, 49.

Russell H Fifield : The Introductory Course in International Relations
(American Political Science Review, Dec. 1948, p. 1190)

पर्यायवाची मान लिया गया है। हम इस बात से तो सहमत हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों की विदेश-नीतियों में चोरी दामन का साथ है, पर यह नहीं माना जा सकता कि दोनों एक हैं अथवा विदेश-नीतियों का अध्ययन मात्र ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति है। सौण्डरमान ने लिखा है कि विदेश-नीति के अध्ययन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का पर्याय नहीं माना जा सकता क्योंकि विदेश-नीति की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र अधिक विस्तृत है जिनमें विदेश-नीति के अध्ययन के अलावा और भी अनेक विषयों का अध्ययन शामिल है।¹ यह सही है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा महत्वपूर्ण ढंग से विदेश-नीति द्वारा की जाती है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की यह महत्वपूर्ण सामग्री है, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन तो इसकी गहराइयों में घुसने का प्रयत्न करना है और यहाँ आकर केवल इस बात से संतोष नहीं हो पाता कि अमुक देश की विदेश-नीति क्या है, बल्कि असलियत जानने के लिए यह देखना पड़ता है कि उस विदेश-नीति को स्वरूप प्रदान करने वाले और उसका नियन्त्रण तथा निर्धारण करने वाले कौन से तत्व और शक्ति-स्रोत हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमें विदेश-नीति को निश्चित करने वाली प्रक्रिया से अवगत कराता है। अध्ययन की यह प्रणाली नवीन है। अमेरिका ने 'निर्णय-प्रक्रिया-प्रणाली' (Decision Making Process) के अध्ययन को अपनाकर विदेश-नीति के अध्ययन की एक उपयोगी और महत्वपूर्ण पद्धति प्रस्तुत की है। विदेश-नीति के अध्ययन को ही सब कुछ मानने के पीछे एक भ्रान्त धारणा यह है कि विदेश-नीति के निर्धारक व्यक्ति ही अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को बनाने, बिगाड़ने व मोड़ने वाले हैं। लेकिन इस बात की उपेक्षा क्यों कर दी जाती है कि कई बार अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण भी नीति-निर्माताओं को कोई विशिष्ट नीति अपनाने के लिए बाध्य कर देता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण तथा विदेश नीति-निर्धारकों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की जानकारी भी सम्मिलित है। रिवसी राइट के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के अन्तर्गत इन बातों का अध्ययन अपेक्षित है—विश्व में तनाव एवं हलचल की सामान्य दशा, आर्थिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक क्षेत्रों में राज्यों की पारस्परिक निर्भरता की मात्रा, कानून एवं मूल्यों का सामान्य स्तर, जनसंख्या तथा साधन, उपज और खपत, जीवन के आदर्श एवं विश्व-राजनीति की स्थिति। इन सभी बातों के कारण हैराल्ड और मॉग्रेट स्पाउट ने विदेश-नीति को, इसकी महत्ता स्वीकार करते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक उप-विभाग बताया है।

स्पाउट के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत राष्ट्रों के उन्ही सम्बन्धों का अध्ययन अपेक्षित है जिनमें किसी न किसी प्रकार का सैनिक या अर्सेनिक सर्वपक्ष विद्यमान है, अन्य प्रकार के सम्बन्धों का नहीं।² स्पाउट का यह भी कथन

1 Fred A. Soudermann's article "The Linkage between Foreign Policy and International Politics" in *The Theory and Practice of International Relations* (New Jersey, 1966), pp.16-23.

2 Harold and Margaret Sprout : *Foundations of International Politics*, p. 76

है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत हम एक ओर तो राजनेताओं और उनके घटकों के दल तथा उनके द्वारा किए गए निर्णयों का ओर दूसरी ओर उन निर्णयों के माधुमिक किए जाने के परिणामों का अध्ययन करते हैं।¹ स्त्राउट ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यद्यपि व्यापकता का समावेश किया है, तथापि सघर्षों के पीछे ओर राष्ट्रों के व्यवहारों के मूल में पड़ने के पीछे छिपी प्रेरक शक्तियों के अध्ययन का महत्व स्पष्ट नहीं किया है।

कुछ अन्य विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र को अपेक्षाकृत विस्तृत या सीमित किया है। चार्ल्स स्लीचर ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को शामिल करने का समर्थन किया है, यद्यपि उसने यह भी माना है कि दल प्रकार के सारे सम्बन्ध केवल राजनीतिक ही नहीं होते।² पामर एवं पर्सिंस ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सीधा सम्बन्ध राज्य-प्रणाली (State-System) से जोड़ा है।³ बर्टन के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में अन्य बातों के अनिश्चित के सभी घटनाएँ और परिस्थितियाँ भी सम्मिलित हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है।" रॉबर्ट स्ट्रॉस-कूप तथा स्टेफन पॉलोनी ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत नागरिकों के कार्यों एवं राजनीतिक दृष्टि में महत्वपूर्ण गैर-सरकारी गुटों के निर्णयों को शामिल करने का समर्थन किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन-क्षेत्र में उपर्युक्त बातों के साथ ही 'विचारधारा' (Ideologies) और 'राष्ट्रीयता' (Nationality) भी प्रमुख हैं। विचारधारा आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख सूत्रधारों में से है। साम्यवाद, नोबतन्त्र, वैयक्तिक स्वतन्त्रता आदि विचारधाराएँ अपने आप में प्रबल शक्तियाँ हैं और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों की प्रेरक हैं। अफ्रीका और एशिया की राजनीति बहुत कुछ राष्ट्रीयता की राजनीति है जिसका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में अफ्रीकाई देशों की राष्ट्रीयता की राजनीति बराबर गुल खिला रही है, बहने की आवश्यकता नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय सस्याएँ और उनसे सम्बन्धित उप-संस्थाएँ, जिनके अध्ययन पर दो महायुद्धों के बीच की अवधि में अधिक जोर था, इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है कि विश्व-समाज को वे एक रूप प्रदान करने और विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में सहयोग और सामञ्जस्य लाने का प्रयत्न करती हैं। आज समुक्त राष्ट्रसंघ का अध्ययन सांविधानिक रूप से चाहे उतना महत्वपूर्ण न हो, लेकिन राजनीतिक सन्दर्भ में उसके कार्यों और उद्देश्यों के अध्ययन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र-संघ और उससे सम्बन्धित अनेक संस्थाओं का विश्व-राजनीति के क्षेत्र और साधन दोनों रूप में अपना स्थान है। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये

1 Ibid, p. 39.

2 Charles S. Schleicher : Introduction to International Relations, p. 31.

3 Palmer and Perkins : International Relations, p. 35.

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कल्पनावादी सम्प्रदाय (Utopian School) के विचारों को कुछ धर्मों में मयार्यना प्रदान करने का काम कर सकती हैं।

शान्ति और युद्ध जैसे विषय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की परिधि में अपने आप समाविष्ट हो जाते हैं। जब संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल में है तो शगला कदम युद्ध हो सकता है और शान्ति विश्व-मानव की ध्याम है। शान्ति और युद्ध से सम्बन्धित विभिन्न समस्याएँ, प्रेरक शक्तियाँ आदि स्वन ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-सामग्री बन जाती हैं।

अन्त में, यह कहा जा सकता है कि जिस ढंग से आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए गम्भीर प्रयास हो रहे हैं तथा उसे एक वैज्ञानिक विषय बनाने के लिए सिद्धान्तों (Theories) की खोज हो रही है, उसके आधार पर यह विषय अपनी परिधि में विभिन्न विषयों को समेटने और अपना क्षेत्र समुचित रूप में व्यापक करने को प्रयत्नशील है।

नामकरण की समस्या (Problem of Nomenclature)

‘अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति’ विषय को व्यक्त करने के लिए ‘अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध’ (International Relations), ‘अन्तर्राष्ट्रीय मामले’ (International Affairs), विश्व-राजनीति’ (World Politics), आदि विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इन सभी नामों का प्रयोग पर्याप्तवाची रूप में कर दिया जाना है तथापि गहराई से देखने पर इन नामों में अन्तर है और अन्तिम विश्लेषण करने पर ‘अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति’ (International Politics) नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त ठहरता है।

सबसे पहले हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दों पर विचार करेंगे। ‘अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध’ शब्दावली में एक व्यापकता है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, रोज एवं अन्वेषण सम्बन्धी और इसी प्रकार के सभी सम्बन्ध आ जाते हैं। इन शब्दों से वास्तव में विविध राष्ट्रों के सम्पर्क, सहयोग, क्रिया-प्रतिक्रिया का बोध होता है अर्थात् ‘सम्बन्धों के जाल’ का अर्थ निकलता है।¹ यह शब्द अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और निजी दोनों ही अन्तःक्रियाओं (Both Public and Private Interactions) को विस्तृत विविधताओं की ओर संकेत करते हैं।² इसके विपरीत ‘अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति’ शब्दावली मुख्यतः राज्यों के राजनीतिक सम्बन्धों तक सीमित है। आशय यह है कि जहाँ पहली शब्दावली से व्यापक सम्बन्धों का बोध होता है, वहाँ दूसरी से एक विशेष प्रकार का। फिर पहली शब्दावली इतनी व्यापक है कि उसके द्वारा

1 Manning : The University Teaching of Social Sciences-International Relations, p. 10.

2 Keith R. Legg and James F. Morrison : Politics and the International System—An Introduction, p. 32.

स्पष्ट भाव में दूसरी शब्दावली (अन्तर्राष्ट्रीय नीति) भी निहित है। स्प्राउट तथा स्प्राउट ने लिखा है कि एक ही व्यापकता में दूसरे को घुसकू करने के लिए ही 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के पद में 'अराजनीतिक' (Non-Political) तत्त्व अधिर है।¹ इस प्रकार 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' शब्दावली विषय-बोध की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में जो विषय-सामग्री निहित है उसरी समीक्षा इस शब्दावली के प्रयोग की उपयुक्तता सिद्ध करती है। राष्ट्रीय-हित (National-Interests), मर्ष (Conflict) और शक्ति (Power) की जिन अवधारणाओं का मकेन पिछले पृष्ठों में किया गया है उनका बोध 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' शब्दावली में अधिक अच्छी तरह समिहित है। यह एक प्रविष्टा की ओर गन्त करती है जिसमें मर्ष उठने है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका समाधान होता है।² किन्तु दूसरी ओर पामर एवं परकिंस जैसे विद्वानों ने दोनों शब्दावलीयों में अन्तर स्वीकार करते हुए भी अपने विषय को 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' कहना ही अधिक उपयुक्त समझा है। उनका मुख्य तर्क यह है कि 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' पर कई विषयों और कई प्रकार के सम्बन्धों का प्रभाव है, घन 'सम्बन्ध' शब्द से राजनीति सही प्रकार समझी जाती है।³

'अन्तर्राष्ट्रीय मामलों' (International Affairs) और 'विश्व-राजनीति' (World Politics) आदि शब्दावलीयों 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' की अपेक्षा कम उपयुक्त हैं और भाव की सूक्ष्मता की दृष्टि में सरी नहीं उतरती। इनमें एक सामान्य भाव का ही बोध होता है, विशिष्ट भाव का नहीं। 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' एक स्वतन्त्र विषय के रूप में जो महत्व प्राप्त करती जा रही है उसके प्रकाश में 'इन्टरनेशनल एफेयर्स' और 'वर्ल्ड पॉलिटिक्स' शब्दों से अधिक व्यापकता अथवा विस्तार का बोध होता है। याव ही विश्व-राजनीति का अर्थ 'विश्व' शब्द के समवेग से कुछ ऐसा बनना है जैसे राष्ट्र को लेकर 'राष्ट्रीय राजनीति' (National Politics) यह अर्थ सभी उपयुक्त है जब एक 'विश्व-राज्य' (World State) हो। इसी प्रकार 'इन्टरनेशनल एफेयर्स' शब्दावली की परिधि में कोई भी सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक घटना आ जाती है जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित हुई हो। अर्थ की निश्चितता के अभाव में 'इन्टरनेशनल एफेयर्स' या 'वर्ल्ड पॉलिटिक्स' शब्दावली विषय के अध्ययन की दृष्टि से लोचप्रिय नहीं है।

नामकरण की यह समस्या तब बहुत-कुछ हल हो जाती है जब हम देखते हैं कि 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' शब्दावली अधिकाधिक प्रचलित होती जा रही है। एक स्वतन्त्र विषय के रूप में इसका महत्व प्रस्थापित हो गया है और विश्वविद्यालयों में इस नामकरण पर आधारित प्रश्न-पत्र और पाठ्यक्रमों का निर्माण होने लगा है।

1 *Sprout and Sprout* : Formulation of International Politics, p. 12.

2 *Legg and Morrison* : Ibid, p. 32.

3 *Falmer and Perkins* : op. cit., XIV.

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भाँति ही आज 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था' (International Political System) की चर्चा उसी तरह होने लगी है जिस तरह आन्तरिक समाज या राज्य में 'राजनीतिक व्यवस्था' (Political System) की होती है। अग्रिम पृष्ठों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था और उसके कतिपय पहलुओं का विवेचन किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था (International Political System)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था एक नई अवधारणा (A New Concept) है।¹ यद्यपि यह व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात् घरेलू राजनीतिक व्यवस्थाओं (Domestic Political Systems) में मौलिक रूप में भिन्न है तथापि राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य अवधारणा (The General Concept of Political System) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कतिपय पहलुओं पर विचार करने में उपयोग हो सकती है। "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को हम क्षेत्रीय आधार पर संगठित अर्द्ध-स्वायत्त-कायूनी और तथ्यात्मक राजनीतिक इकाइयों के एक मंड (A Set) के रूप में देख सकते हैं। इन राजनीतिक इकाइयों का अभिप्राय राष्ट्रों अथवा राज्यों (Nations or States) से है जो इस विश्व को घेरे हुए हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न विवाद-क्षेत्रों (Issue Areas) में एक दूसरे के प्रति स्वतन्त्र और सामूहिक रूप से कार्य करते हैं।"² राज्य राजनीतिक संगठन का एक विशिष्ट रूप है, यह क्षेत्र-विशेष के नियन्त्रण का दावा करता है और विभिन्न रूपों में अन्य राज्यों के साथ आन्त.क्रिया करता है। इनमें से एक रूप या तरीका अपनी प्रादेशिक एकात्मता अथवा नियन्त्रण कायम रखता है। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को हम उन राज्यों की एक व्यवस्था कह सकते हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी सीमाओं में अपने नियन्त्रण का दावा करता है और घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर उस नियन्त्रण को कायम रखने के लिए कार्य करता है।³ यह बात अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा से सम्बन्धित नहीं है कि कोई राज्य अपने नियन्त्रण का विस्तार किसी दूसरे राज्य के प्रदेश पर करने का प्रयत्न करता है या नहीं। इसी प्रकार इस परिभाषा में यह बात भी नहीं आती कि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों की प्रादेशिक एकात्मता (Territorial Integrity) का सम्मान करेगा अथवा प्रत्येक राज्य केवल

1 William D. Coplin : Introduction to International Politics—A Theoretical Overview, Second Edition, 1974, p. 329-331.

2 "The international political system may be viewed as set of semi-autonomous—in law and in fact—political units organized on a territorial basis. Called nations or states, these political units that now encompass the earth act independently and collectively toward each other in a large number of issue areas."
—William D. Coplin : Ibid, p. 329.

3 "The international political system is a system of states, each of which claims control within its boundaries and acts to maintain that control domestically and internationally."
—William D. Coplin : Ibid, p. 330.

माने ही प्रदेश के नियन्त्रण और सुरक्षा का दावा करेगा। इन बातों के प्रकाश में यह व्यवस्था (अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था) ऐसी प्रतीत होती है मानो कि हम सिंगी व्यवस्था (Non-System) की बात कर रहे हों क्योंकि इस व्यवस्था में कार्यकर्ताओं (Actors, राज्य) पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है न कि उन कानूनों और संस्थाओं पर जो कार्यकर्ताओं के व्यवहार को ढाँकते हैं। हमारा जोर या प्राग्रह (Emphasis) राज्य पर है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था 'विशेन्द्रीकृत' (Decentralized) होती है। अन्तर्राष्ट्रीय अन्तःक्रियाओं के लिए वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक गठित (The Legal, Social and Economic Settings) विवेन्द्रित होते हैं और टुकड़ों-टुकड़ों में विभाजित होते हैं तथा स्वतन्त्रतापूर्वक आचरण करने वाले विभिन्न राज्य ऐसे नाजुक निर्णय (Crucial Decisions) से बैठते हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून और विश्व-अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसी प्रकार, राज्यों के मध्य राजनीतिक दशाओं का निर्धारण भी उन निर्णयों से होता है जो राज्यों द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में कार्य करते हुए किए जाते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्रमण्डल अथवा विश्व न्यायालय जैसी केन्द्रीय संस्थाएँ मौजूद हैं, तथापि उनकी सत्ता राज्यों की इच्छा द्वारा सीमित है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता दुर्बल होती है और राज्यों की गतिविधियाँ ही व्यवस्था में महत्वपूर्ण दशाओं का निर्धारण करती हैं, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रवर्तन करना महत्वपूर्ण है। व्यवहारों और गतिविधियों के कुछ प्रतिमान (Patterns) नौकड़ों सालों से चलते आ रहे हैं। उदाहरणार्थ, क्षेत्रीय आधार पर संगठित अर्द्ध-स्वायत्त राजनीतिक इकाइयों के रूप में इस व्यवस्था (अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था) की चुनौतियों का सामना राज्यों ने सामूहिक रूप से किया है। इसी प्रकार अनेक कारण भी इस बात को महत्व प्रदान करते हैं कि हम राज्यों में घटनाओं की समग्रता पर (At the Totality of Events Among Nations) एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में दृष्टिपात करें। संयुक्त राष्ट्रमण्डल जैसे अन्तर्सरकारी संगठनों (Inter-governmental Organizations) के विनाश के प्रतिरिक्त राज्यों द्वारा एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को उपयोगी बनाता है। इस प्रकार अन्तर्हस्तक्षेप (Interpenetration) दीर्घकाल में राज्य को एक राजनीतिक संगठन के रूप में कम आत्म-निर्भर (Less Viable) बना कर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सम्पूर्ण संरचना को बदल सकते हैं अथवा ये अधिक विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जन्म दे सकती हैं। उलझने जो भी पैदा हो या हम निहितायें कुछ भी लें, ये विभिन्न कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रतियोगी राज्यों की केवल अराजकतापूर्ण गतिविधियों से कुछ अधिक ही विस्तृत बनाते हैं।

सारांश में, "राज्यों के बीच अन्तःक्रियाओं के औपचारिक और अनौपचारिक ढंगों या आदर्शों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है।

यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था विकेन्द्रीकृत होती है क्योंकि केन्द्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, जो अस्तित्व में हैं, बहुत कम सत्तापूर्ण हैं।¹ इसके प्रतिरिक्त, राज्यों के बीच जो अन्तःक्रियाएँ होती हैं उनसे ऐसे व्यवहार-प्रतिमानों (Patterns) का जन्म हुआ है जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएँ हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न है स्वायत्त राज्यों की एक व्यवस्था का संपोषण (Maintenance of a System of Autonomous States)।¹¹

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का संपोषण (Maintaining the International Political System)

विनियम डी. कोपलिन (William D. Coplin) ने अपनी पुस्तक 'Introduction to International Politics' के चारहवें अध्याय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कायम रखने की समस्या और समय-समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों की विवेचना की है।¹² कोपलिन के अनुसार, लगभग 1648 से ही निरन्तरता का एक ऐसा मूत्र दिखाई देना है जिसमें यह प्रकट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखने में राज्यों ने परस्पर सहयोग किया है। कोपलिन ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि भूतकाल में राज्यों का व्यवहार कैसा रहा और आज भी एक विश्व राजनीतिक संगठन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखने में राज्यों की गतिविधियाँ कैसी हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व का निश्चय करने में घरेलू राजनीति में केवल यही देखना होता है कि कतिपय केन्द्रीय संस्थाएँ कार्य कर रही हैं या नहीं अर्थात् वे सत्तापूर्ण क्रियाशील हैं या नहीं जो व्यवस्था को आन्तरिक गड़बड़ और बाह्य आक्रमण दोनों चुनौतियों से सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं—जैसे पुलिस और न्यायालय तथा सशस्त्र सेनाएँ। इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी कोई केन्द्रीय संस्था नहीं होती जिनके सतत कार्य इस व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक समझे जाएँ जैसे कि पुलिस, न्यायपालिका तथा सशस्त्र सेना घरेलू राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक मानी जाती है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के विनाश का खतरा पैदा हो सकता है, तथापि इसका यह मतलब नहीं है कि इस व्यवस्था का विनाश अवश्यमेव हो ही जाएगा। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्रसंघ की पुलिस और सैनिक शक्ति के अभाव का अर्थ होगा संयुक्त राष्ट्रसंघ का, एक प्रभावकारी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अस्त। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ निर्बल हैं, हम उनके निरन्तर अस्तित्व और कार्य-व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कायम रखने का संकेत नहीं मान सकते। इसी वजह से हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के केन्द्रीय संरचनात्मक तत्वों (Central Structural Features) पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए अर्थात् प्रादेशिक क्षेत्र पर आधारित एक स्वायत्त राजनीतिक संगठन के रूप में राज्य पर ध्यान देना।

1 Ibid, p. 360.

2 Ibid, pp. 332-362.

चाहिए। यदि हम मान लें कि अपने आन्तरिक मामलों के नियमन में अपेक्षाकृत स्वतंत्र राज्यों के समूह वा अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था वा आधारभूत स्वरूप रहा है तो हम एक राजनीतिक संगठन के रूप में राज्यों की व्यवस्था की प्रस्तुत चुनौतियों की जाँच करके उस तरीके वा विस्तारण कर सकते हैं जिससे अनुगार वा जिनके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था कायम रही गई है।¹ विलियम वोपलिन के अनुगार इस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को दो प्रमुख चुनौतियों (Threats) वा सामना करना पड़ा है और ये हैं, सार्वभौमिक साम्राज्य (Universal Empire) और बड़े पैमाने पर युद्ध (Large-scale War)। वोपलिन ने इस बात पर विचार किया है कि ये चीजें से तरीके रहे हैं जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था ने सम्मुख प्रस्तुत इन दो चुनौतियों ने अर्थात् तीन ऐतिहासिक युगों में व्यवहार के वृत्तिप्रतिमानों (Patterns of Behaviour) को सुदृढ़ बनाया है—

- (i) पुरातन व्यवस्था (The Classical System), 1648-1815,
- (ii) संक्रमणवादी व्यवस्था (The Transitional System), 1815-1945,
- (iii) समकालीन व्यवस्था (The Contemporary System), 1945 से आज तक।

चूँकि ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की प्रवृत्ति के अनुगार कोई बँडोर विभाजक रेखा नहीं हो सकती, अतः तीनों ऐतिहासिक युगों की उपर्युक्त तिथियों को हम सामान्य मार्ग-दर्शक रेखाओं के रूप में लेना चाहिए।

पुरातन व्यवस्था कायम रखना
(Maintaining the Classical System)

पुरातन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था (The Classical International Political System) वा अस्तित्व यूरोप में सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से फ्रांसीसी क्रांति और 1815 के नेपोलियन-युद्धों तक रहा। इस पुरातन ऐतिहासिक युग के कुछ पहलू सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से भी पहले के थे तो कुछ 1815 के बाद के। इस युग में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व को मुख्य चुनौती साम्राज्य-निर्माण की ओर से मिली, बड़े पैमाने पर युद्ध को उस समय एक गौण चुनौती समझा गया। विलियम वोपलिन ने इस युग की अर्थात् पुरातन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की अनेक आधारभूत विशेषताओं की ओर संकेत किया है—

1. इस व्यवस्था के सदस्य यूरोपीय राज्य थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी सोवियत संघ के अन्य राष्ट्र अपने आन्तरिक विकास में लगे हुए थे और स्वयं की

1 "If we assume that the basic nature of the international political system has been the existence of a group of states relatively free to regulate internal matters, we can analyze the way in which the system has been maintained by examining the threats to the system of states as a form of political organization."

—William D. Coplin : Ibid, p. 333.

आर्थिक नहीं तो राजनीतिक दृष्टि से यूरोप से पृथक् मानते थे। यूरोपीय राज्य भी विश्व के गैर-यूरोपीय क्षेत्रों की उपेक्षा करते थे। इस प्रकार कुल मिला कर पुरातन युग के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था यूरोपीय राज्यों की आपसी अन्त-क्रियाओं के प्रतिमान (Consisted of patterns of Interactions among European States) में सन्निहित थी। उस समय फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया महाशक्तियाँ (The Great Powers) थी और ग्रेट-ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड्स टर्की तथा प्रशिया महाशक्ति का स्तर (Great Power States) पाने की आकांक्षा रखते थे, हालाँकि वे काफी समय तक वास्तव में इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके। यूरोपीय राज्य विश्व के गैर-यूरोपीय क्षेत्रों को अपने आपसी मंथन में मोहरो की तरह समझते थे। इसी प्रकार स्वयं यूरोप में भी जो सैकड़ों छोटे-छोटे राज्य थे उन्हें यूरोप के बड़े राज्य आपसी झगड़ों में मोहरो के रूप में प्रयोग करने को लावायिन रहते थे। बड़े और छोटे राष्ट्रों में यह एक मुख्य अन्तर था। सारांश में पुरातन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी शक्तियाँ छोटी शक्तियों को अपने प्रभाव में रखती थी।

2. बड़ी शक्तियाँ (Major Powers) एक-दूसरे पर सीधा आक्रमण करने की अपेक्षा औपनिवेशिक प्रदेशों और लघु शक्तियाँ (Small Powers) पर नियन्त्रण के प्रश्न पर लड़ती थी।

3. निर्णायक शक्तियाँ नीति को प्रभावित करने वाली शक्तियों पर हावी रहती थी। तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अधिकांश राज्यों का आन्तरिक ढाँचा इस प्रकार का था कि निर्णयकर्त्ताओं (Decision makers) को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से निपटने की दृष्टि से काफी छूट थी। वह युग ऐसा था जिसमें सरकार के लोकतान्त्रिक स्वरूपों का विकास केवल शुरू ही हुआ था और औद्योगिक क्रांति ने राजनीतिक व्यवस्था को उस आधुनिक स्वरूप में रूपान्तरित नहीं किया था जिसमें नीतियों को प्रभावित करने वाले लोग (Policy influencers) की बड़ी माँग होती है। यही कारण है कि पुरातन युग में (In the Classical Period) बहुत ही लचीली विदेश नीतियों का अनुसरण करना सम्भव था।

4. सामाजिक-सांस्कृतिक बन्धन (Socio-cultural Ties) युद्धों की तेजी को सीमित कर देते थे। चूँकि पुरातन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य यूरोपीय राज्य ही थे, अतः सामाजिक-सांस्कृतिक बन्धनों के कुछ ऐसे सामान्य सूत्रों का अस्तित्व था जो सभी राज्यों को या कम से कम ज़ेप विश्व सम्बन्धी मामलों में परस्पर संगठित रखते थे। ये सामाजिक-सांस्कृतिक तत्व अधिकांश राज्यों के नेताओं को इस इच्छा को बल प्रदान करते थे कि लम्बे युद्धों को टाला जाए और ऐसे कदमों को उठाने से बचा जाए जिनसे सम्पूर्ण व्यवस्था के पंगु हो जाने का भय हो।

5. सामाजिक-सांस्कृतिक बन्धनों की भाँति ही प्राविधिक या तकनीकी तत्व (Technological Factors) भी युद्धों की भीषणता को सीमित रखने में सहायक थे। उदाहरणार्थ, स्पष्ट पर वह युग पुइसवारी और पैदल सैनिकों का था और समुद्र

पर उम समय तक बाण नौराएँ महत्वपूर्ण मैनिक तत्व के रूप में नहीं उभरी थी। रेनो का मैनिक दृष्टि से महत्व स्थापित नहीं हो सका था। इस प्रकार पौत्रों की शक्तिशीलता बहुत बढ़ी-बढ़ी नहीं थी। इसके प्रतिरिक्त, छात्र की तुलना में आग्नेयास्त्र (Fire arm) भी बहुत कम विकसित थे। उम समय महामारियों या गम्भीर बीमारियों को भी नियन्त्रित कर सकना एक दुर्लभ काम था।

6. किसी एक शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बायम रखने का पुराना ढंग यह था कि विरोध में एक सन्तुलनकारी गठबन्धन या गुट (A Balancing Coalition or Alliance) बना लिया जाता था।

7. सन्तुलनकारी गठबन्धन या गुट बनाने का ढाँचा प्रचली तरह इसीलिए कार्य करता रहा क्योंकि विदेश नीति के निर्णायकतामो (Foreign Policy Decision Makers) के लिए सचीनी विदेश नीतियाँ अपनाना सुगम था।

8. सचीनी विदेश नीति, सामाजिक-नास्तृनिक बन्धन और प्राविधिक या तकनीकी तत्व—ये सब मिलकर बड़े पैमाने पर युद्धों को रोकने में मह्योग देने थे।

पुराना युग में यद्यपि यूरोप में साम्राज्य-निर्माण की चुनौती बायम रही तथापि उपर्युक्त विभिन्न कारकों और विरोधतामो के बल पर बिनाशकारी बड़े पैमाने के युद्धों को रोका जा सका और पुराना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बायम रखा जा सका।

संक्रमणकालीन व्यवस्था को कायम रखना
(Maintaining the Transitional System)

हमने 1815 से 1945 तक के युग को संक्रमणकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का युग माना है। इस युग में पुराना राजनीतिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। विलियम कोपलिन ने इस संक्रमणकालीन व्यवस्था में हुए परिवर्तनों के आधारभूत तथ्यों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है और यह भी बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था बायम रखने की दृष्टि से इन परिवर्तनों के क्या परिणाम निकले—

1. व्यवस्था की सदस्यता का प्रसार यूरोप के बाहर भी होने लगा अर्थात् . . . का विश्वव्यापी रूप (Universalization of the System) हुआ। 1815 में संयुक्तराज्य अमेरिका के सिवाय व्यवस्था के सभी राज्य यूरोपीय थे। संयुक्तराज्य अमेरिका का प्रवेश कभी-कभी हो जाता है। किन्तु 1945 तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य सत्तार भर में फैल गए, उपनिवेशों के रूप में ही नहीं बल्कि ऐसे शक्तिशाली राज्यों के रूप में भी जिनसे कि बराबरी का बर्ताव करना होता था।

2. विदेश नीति के निर्णायकतामो को अब नीतियों को प्रभावित करने वाली शक्तियों (Policy Influencers) के आन्तरिक दबावों का सामना करना पड़ा, अर्थात् ये 'पॉलिसी इनफ्लूएंसर्स' भी महत्वपूर्ण बन गए।

3. पहले शक्ति के प्रयोग पर जो सामाजिक-सांस्कृतिक सीमाएँ (Socio-cultural Limitations) लगी थी, ये गायब हो गईं। सत्रमणुसाल में यद्यपि यातायात और संचार-वाहन के साधनों में प्रसार हुआ और उनमें गति आई, लेकिन उनसे राष्ट्रों के भौतिक सहयोग में तो वृद्धि हुई पर राष्ट्रों के बीच सहयोग की प्रेरणा नहीं मिली।

4. प्राविधिक प्रगति (Technological Progress) ने राष्ट्रों की एक दूसरे को हानि पहुँचाने की क्षमता को बढ़ा दिया। वाष्पयानों, वायुयानों आदि के कारण राष्ट्रों की सैनिक गति की क्षमता (Mobility of military capability) बहुत अधिक बढ़ गई और इसके विनाशकारी परिणाम द्वितीय महायुद्ध में देखने को मिले।

5. सार्वभौमिक या विश्व-साम्राज्य (Universal Empire) में अभिरुचि के स्थान पर क्षेत्रीय साम्राज्य (Regional Empire) में अभिरुचि बढ़ने लगी।

6. विदेशनीति के निर्यातों में लचीलापन कम हो गया।

7. प्रथम महायुद्ध के बाद से ही बड़े पैमाने के युद्ध का भय (Fear of large scale war) बढ़ गया जिसके फलस्वरूप 'शान्ति अविभाज्य है' (Peace is indivisible) जैसे नारे लगाए जाने लगे और निश्शस्त्रीकरण के प्रयत्न होने लगे।

8. सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त (Principle of collective security) का महत्व बढ़ा और सन्तुलनकारी गठबन्धन के संस्थानीकरण के लिए एक प्रभावी तर्क के रूप में (An Argument for institutionalization of the Balancing Coalition) इसे पेश किया जाने लगा।

9. सामूहिक सुरक्षा-सिद्धान्त के बावजूद दो महायुद्धों के बीच की अवधि में सन्तुलनकारी गठबन्धनों का निर्माण (Formation of a Balancing Coalition) बहुत धीमा हुआ।

10. फ्रांस और इंग्लैंड की 1930 के दशक की विदेश-नीतियों में सम्भावित युद्ध का भय दिखाई देता था जिसके कारण हिटलर को रोकने के किसी सन्तुलकारी गठबन्धन के निर्माण के प्रयत्नों को धक्का लगा। जापान या जर्मनी के आक्रामक रुखों के विरोधी राज्यों ने प्रतिरोधी गठबन्धन (Counter-Coalition) बनाने की चेष्टा नहीं की। ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीतियों की कमजोरी के फलस्वरूप जर्मन चुनौती के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सका और युद्ध टालने के आवरण में टुट्टिकरण की ऐसी नीति अपनाई गई जिसने जर्मनी के आक्रामक साहस को बहुत अधिक बढ़ा दिया।

इस प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक का युग स्पष्ट रूप से सत्रमणकालीन (Transitional) था। राज्य-व्यवस्था के सार्वभौमीकरण (Universalization of State System) ने विश्व-साम्राज्य की चुनौती को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार दिया और प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सन्तुलन (Regional

Balances) अधिक महत्वपूर्ण बन गए। पुरातन युग (Classical Period) में निर्णायकताओं की अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के गन्दम में सुनी छूट प्राप्त थी, वह अब नहीं रही क्योंकि तब-हीनी प्रगति से व्यापक सैनिक योजनाओं की आवश्यक बना दिया और परेन् राजनीतिक व्यवस्थाएँ ऐसी बन गई कि नीति को प्रभावित करने वाली शक्तों प्रदानता प्राप्त करने लगी। सत्रमणकालीन युग में महायुद्धों की चुनौती बढ़ गई क्योंकि एक तो सैनिक क्षमता में विस्तार हुआ और दूसरे सामाजिक तथा गौणता वगैरह भी शामिल पड़ गए। यद्यपि युद्ध के भय के फलस्वरूप कुछ सीमाएँ लगी रही, लेकिन ये इतनी प्रभावकारी नहीं थी जो रिगो बड़े युद्ध को रोक पाती। इसके अनिश्चित ये सीमाएँ सार्वभौमिक नहीं थी और हिटलर तथा मुसोलिनी के रूप में ऐसे निर्णायकता मौजूद थे जो आत्म-रक्षा से भिन्न दूसरी चीजों के लिए भी शक्ति के प्रयोग के लिए तालावित थे। हिटलर और मुसोलिनी उन लोगों में से थे जिनके लिए शान्ति मृत्यु थी और युद्ध जीवन। दो महायुद्धों की बीच की अवधि में हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों ने उन राज्यों को खूब टगा जो युद्ध के भय में आतन्त्र थे और रिगो भी प्रकार युद्ध को टालने की इच्छा रखते थे। प्रथम महायुद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण के प्रयासों ने तेजी पकड़ी थी, लेकिन ये प्रयास असफल रहे और भावी महायुद्ध को रोक नहीं जा सका। राष्ट्रमण शान्ति को स्थापित करने और युद्धों को रोकने के मन्त्र के रूप में असफल रहा। चूंकि राष्ट्रों को निःशस्त्रीकरण और राष्ट्रमण दोनों में सन्देह रहा, अतः वे अपनी सुरक्षा के लिए चिन्तित हुए और उन्होंने सन्तुलनकारी सन्धियों या गुटों के निर्माण का परम्परागत साधन अपनाया। उनका प्रयत्न प्रयत्न रहा कि सार्वभौम या क्षेत्रीय साम्राज्य-निर्माण अथवा युद्ध के विस्तार को रोक जाए। तीस के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीतियाँ सम्भावित युद्ध के भय से उत्पन्न कमजोरियों का शिकार बनीं रही, अतः न तो हिटलर और मुसोलिनी के सर्वप्राप्ति रूप के विरुद्ध सन्तुलनकारी गुट का निर्माण किया जा सका और न सामूहिक सैनिक शक्ति का प्रयोग ही हो पाया। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए महायुद्ध की गम्भीर चुनौती बनी रही।

समकालीन व्यवस्था को कायम रखना

(Maintaining the Contemporary System)

समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था पुरातन और सत्रमणकालीन दोनों युगों की व्यवस्था से अपेक्षाकृत भिन्न है। द्वितीय महायुद्ध में धन-जन का भीषण विनाश हुआ और युद्ध की परिसमाप्ति नागासाकी तथा हिरोशिमा पर अणुबमों के प्रत्यक्षकारी प्रहार के साथ हुई। महायुद्ध की घटनाओं और परिणामों ने उस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया जो सामयिक परिवर्तन के साथ आज तक चल रही है। विलियम कोपलिन के अनुसार इस वर्तमान व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं—

1. द्वितीय महायुद्ध के अन्त में आणविक हथियारों के प्रयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय

राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने की दिशा में एक नए तत्व का प्रवेश कर दिया और वह तत्व है—युद्ध के भय की तीव्रता (Intensifying Fear of War)। द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व में पहले संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत संघ ही इनने क्षमता सम्पन्न थे जो न केवल एक दूसरे का विनाश करने बल्कि विश्व के अधिकांश भाग को नष्ट करने की शक्ति रखते थे। तत्पश्चात् भय और भी राष्ट्र प्रभु और परमाणु आयुधों से सज्जित हो गए हैं, और आज आणविक शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों में प्रत्यक्ष युद्ध की रोकने की आवश्यकता अन्य किसी भी समय से अधिक महत्त्व की जा रही है। यह समझा जाने लगा है कि ऐसा कोई भी युद्ध समूची प्रन्तराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक भयावह चुनौती है।

2. राज्य-व्यवस्था पूरी तरह विश्वव्यापी बन चुकी है। आज विश्व का लगभग प्रत्येक राज्य प्रन्तराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का सदस्य है और इस बात का व्यवस्था के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ा है। यद्यपि दो सर्वोच्च महा शक्तियाँ एक दूसरे पर विश्व-प्रभुत्व के प्रयत्नों का आरोप लगाती हैं, तथापि यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी एक शक्ति द्वारा विश्व-साम्राज्य का यह भय यथार्थ न होकर काल्पनिक है।

3. सार्वभौमिक भयवा विश्व-प्रभुत्व की बात तो आज मिस्या लगती है, किन्तु क्षेत्रीय प्रभुत्व (Regional Dominance) की चुनौती वास्तविक है और इस दिशा में बड़े तथा शक्तिशाली राज्यों में प्रतिस्पर्धा है। विश्व के किसी भी राष्ट्र के पास आज इतनी जबरदस्त मैनोफ और आर्थिक शक्ति नहीं है कि वह मारे संसार पर राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित कर सके—विशेषकर वहाँ जहाँ की जनगणना उसका दुश्मनापूर्वक विरोध करती हो। छापामार युद्ध-प्रणाली (Guerrilla Warfare) ने विश्व-साम्राज्य की धारणा की घम्झियाँ उड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भूना की है। यदि एक शक्तिशाली राज्य किसी प्रदेश को जीत भी लेता है तो भी उस प्रदेश के निवासी भीषण छापामार युद्ध द्वारा उस शक्तिशाली राज्य को अपनी विजय के साधों से ही वंचित नहीं कर पाते बल्कि उसने लिए और भी अनेक विफल परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। विद्यमानियों के छापामार युद्धों में अमेरिका जैसी महाशक्ति को कितना छद्म-भय दिया, वहने की आवश्यकता नहीं। पुनश्च, हाल ही के इतिहास ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि गैरान्वितिक विफलता भयवा आर्थिक सहयोग का आश्रय राजनीतिक नियन्त्रण नहीं है। सम्पुनित कूषा अपनी गैरान्वितिक सहानुभूति और आर्थिक परतन्त्रता के बावजूद चीनी या सोवियत 'साम्राज्य' का भग नहीं है। इस प्रकार आधुनिक परिस्थितियों में, विश्व-साम्राज्य का भय प्रन्तराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए कोई वास्तविक चुनौती नहीं रह गया है। हाँ, क्षेत्रीय साम्राज्य का भय अवश्य मौजूद है और अनेक राज्यों की नीतियों को गतिशील बनाए हुए है। यही कारण है कि आज के युग में क्षेत्रीय युद्ध (Regional Wars) सामान्य बन गए हैं। क्षेत्रीय हितों को लेकर राज्यों में युद्ध होते रहते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान में तथा इराक़लियों और अरबों में जब तब युद्ध होते रहे

है। यह भी हुआ कि दोनों महाशक्तियों तथा कुछ अन्य राज्यों ने मध्य में मोर्चा बनाए रखने के लिए दो-दो प्रतिरोधी पक्षों पर दबाव डाला है। यह दबाव कभी तो परामर्श के रूप में और कभी समर्थन देने में दूसरी के रूप में, कभी आधिक गहायता बन्द करके तो कभी सैनिक मामलों को दो-दो पर प्रतिशब्द लगा कर, कभी अन्य प्रकार के दृष्टी-निर्देश दबाव द्वारा डाले जाने रहे हैं। विनियम कोशित के अनुसार समवाचीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महाशक्तियों ने मुख्य रूप से तीन प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है—

- (क) जिन क्षेत्रों में उनके अपने हित हैं, वहाँ वे स्वयं स्थापित कायम रखने का प्रयत्न करते हैं।
- (ग) कुछ क्षेत्रों में वे मध्य और क्षेत्रीय मामलों को रखने में परस्पर सहयोग करते हैं।
- (ग) कुछ क्षेत्रों में वे विरोधी पक्षों को समर्थन देकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरणार्थ, पश्चिमी एशिया में समुन्तराज्य अमेरिका द्वारापन का पृष्ठपोषण करता है तो सोवियत संघ अरब राष्ट्रो का।

4. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में यह भी एक घाम बात हो गई है कि महाशक्तियाँ कुछ दिग्गजों से पहले ही क्षेत्रीय मामलों में बढ़ावा सत्तार हो जाती हैं। द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में क्षेत्रीय 'सुरक्षा संगठनों' (Regional Security Organizations) की तत्पनीक का विभाग हुआ है जो बहुत कुछ क्षेत्रीय गठबन्धनों (Regional Alliances) जैसी दिताई देनी हैं। समुन्तराज्य अमेरिका ने नाटो, दक्षिण-एशियाई सन्धि संगठन, केन्द्रीय-सन्धि संगठन, अमेरिकी राज्यों का संगठन एंजुस परिषद् (NATO, The South Asian Treaty Organization, the Central Treaty Organization, the organization of American States, the Anzus Council) जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों की स्थापना की है तो दूसरी ओर सोवियत संघ ने वारसा पॅक्ट (Warsaw Pact) संगठित किया है।

5. महाशक्तियाँ गृह युद्धों में भाग लेकर भी क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करती रही हैं। रूस और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियों ने गृह युद्धों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किए हैं। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1960 के प्रारम्भिक वर्षों में साइप्रस के गृह-युद्ध में दृष्टी-निर्देश किया तो 1965 में डॉमिनिकन गणराज्य में सैनिक हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ ने 1956 में हंगरी में हस्तक्षेप किया तो 1968 में गृह-युद्ध दिग्गजों का बहाना लेकर चेकोस्लोवाकिया में सैनिक हस्तक्षेप किया। महाशक्तियों ने इस पुरातन अवधारणा पर आचरण करते हुए कि एक राज्य में गृह-युद्ध या घरेलू गडबडी विस्तारवादी राज्यों को नियन्त्रण का आमान्त्रण देती है, उन राज्यों में जो कि गृह-युद्ध से पीड़ित थे या जिनके समक्ष गृह-युद्ध की चुनौती प्रस्तुत थी, राजनीतिक स्थापित्व बनाए रखने का प्रयत्न किया है।

6. उन क्षेत्रों में जहाँ महाशक्तियों ने मटमूल किया कि किसी एक महाशक्ति का यहाँ प्रभुता विशिष्ट हित है, हस्तक्षेप एकपक्षी रहा है। उदाहरणार्थ, पश्चिमी गोलार्द्ध के किसी भी राज्य में घरेलू गड़बड़ी की सूरत में भ्रष्ट संयुक्तराज्य अमेरिका का हस्तक्षेप सामान्यतः पर्याप्त समझा जाता है। यह हस्तक्षेप प्रत्यक्ष भी हो सकता है जैसा कि 1965 में डॉमिनीकन गणराज्य में सेनाएँ भेजकर अस्थिरता के समय नूटनीतिक तथा अन्य दबाव डालकर किया गया। पूर्वी यूरोपीय राज्यों में सोवियत संघ के विशेष हित हैं, अतः इन राज्यों में घरेलू व्यवस्था के प्रति वह विशेष चोखन्ना रहता है। 1950 के दशक में हङ्गेरी, पोलैण्ड तथा पूर्वी जर्मनी में हस्ती सैनिकों ने हस्तक्षेप किया और यही बात 1968 में चेकोस्लोवाकिया में हुई और कुछ हद तक शिम्यर, 1981 में पोलैण्ड में हुई। सम्भवतः दोनों महाशक्तियों में इस बात पर अप्रत्यक्ष सहमति हो गई है कि अपने-अपने हित-क्षेत्रों में यदि घरेलू राजनीतिक अस्थिरता की चुनौती प्रस्तुत हो तो अपने-अपने महाशक्ति उस चुनौती से निबट ले चाहे प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के विरुद्ध वक्तव्य दें। इस प्रकार जहाँ पश्चिमी गोलार्द्ध भ्रष्ट संयुक्तराज्य अमेरिका के लिए छोड़ दिया गया है वहीं पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के लिए छूट है।

7. कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी यूरोप में, घरेलू अस्थिरता आम तौर पर दोनों महाशक्तियों में सहमति और संघर्ष की दशाएँ उत्पन्न कर देती है। यद्यपि कभी-कभी इन मामलों में वे संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से सहयोग करती हैं, जैसा कि 1960 में बांग्लादेश में हुआ, परन्तु ऐसा सहयोग प्रायः अल्पकालिक होता है। बांग्ला में भी दोनों शक्तियों में सहयोग अल्पकालिक रहा था क्योंकि सोवियत संघ ने अनुभव किया कि संयुक्तराज्य अमेरिका वहाँ राजनीतिक शक्तियों से निपटने में तटस्थ मार्ग का अनुसरण न कर पक्षपात की नीति पर चल रहा था। ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाती है कि अग्रान्त या चुनौती-ग्रस्त राज्य में संयुक्तराज्य अमेरिका तो पश्चात्तत्त्व शक्तियों (Status-quo Powers) की रक्षा करता है जबकि सोवियत संघ क्रान्तिकारी शक्तियों (Revolutionary Powers) को समर्थन देता है। उदाहरणार्थ, 1940 के दशक के उत्तरार्द्ध में अमेरिका ने ग्रीस और टर्की को इसलिए मदद दी कि वह समझता था कि सोवियत संघ द्वारा समर्थित राजनीतिक गुट वहाँ की राजनीतिक स्थिरता को चुनौती दे रहे थे। 1960 के दशक में वियतनाम संघर्ष में यही प्रतिमान (Pattern) दिखाई दिया। संयुक्तराज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में सक्रिय हस्तक्षेप शुरू कर दिया और यह निर्णय अमेरिका की इस विदेशी नीति पर आधारित था कि मौजूदा शासन की रक्षा कर क्षेत्रीय व्यवस्था में स्थायित्व कायम रखा जाए। यद्यपि प्रारम्भ में सोवियत संघ ने वियतनाम में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया तथापि जब अमेरिका का निर्णय उत्तर वियतनामी शासन के विरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप की सीमा तक जा पहुँचा तो सोवियत संघ ने भी क्रान्तिकारी शक्तियों को पूर्ण समर्थन देने की तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई।

8. विदेश-नीति में निर्णय लेने का कार्य (Foreign Policy Decision Making) आज पूर्वापेक्षा कम गंभीर हो गया है क्योंकि एक तो नीति-प्रभावकारियों (Policy Influencers) की भूमिका विदेश-नीति-निर्माण में बढ़ती जा रही है और दूसरे प्राविधिक स्थितियों (Technological Conditions) ने गठबन्धनों को अधिक स्थिर (Static) बना दिया है। आज लगभग प्रत्येक राज्य में एक दोहरी नीति प्रभाव-प्रणाली (Pluralized Policy Influence System) है जिसके घनगुन एक और तो निर्णय करने वाले (Decision Makers) हैं और दूसरी और नीति को प्रभावित करने वाले (Policy Influencers)। फिर स्थिति यह है कि विदेश-नीति के निर्माण में इन नीति प्रभावकारियों (Policy Influencers) की माँग बढ़ती जा रही है और उनके दबाव के आगे निर्णयकर्त्ताओं (Decision Makers) को झुकना पड़ता है। दूसरी और विभिन्न गठबन्धनों (Alliances) की प्रवृत्ति भी पूर्वापेक्षा काफी बढ़ान गई। आज के सैनिक गठबन्धन मेनाघों के आदान-प्रदान और अन्य प्रकार के सैनिक सहयोग की माँग करते हैं। उदाहरणार्थ, अमेरिकी पॉज विश्व के लगभग उस प्रत्येक राज्य में सैनिक हैं जो संयुक्तराज्य अमेरिका से सैनिक गठबन्धन में बँधा हुआ है। इस प्रकार के सैनिक सहयोग ने गठबन्धनों को पुरातन युग (Classical Period) की अपेक्षा अधिक स्थायी (Stable) बना दिया है क्योंकि जहाँ गठबन्धनों के उपकरणों पर सामों डॉनरो और बड़ी मर्या में व्यक्तियों का विनिमय होता है वहाँ इस बात की सम्भावना बहुत कम रहती है कि गठबन्धन प्रतिमानों (Alliance Patterns) को निरन्तर बदला जाए। आज के सैनिक गठबन्धन या गठबन्धन अपने सभी सदस्यों के हाथ बँधे रहते हैं (Military alliances tie the hands of all members of the alliance)।

9. लचीलेपन की बमी ने शक्ति-सन्तुलन और सामूहिक सुरक्षा दोनों की कार्यक्षमता (The operation of both the balance of power and collective security) को सीमित बना दिया है।

10. क्षेत्रीय साम्राज्यों (Regional Empires) को रोकने के लिए संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ने विश्वव्यापी धोड़सी की व्यवस्था (Universal Surveillance) अपनाई है। महाशक्तियाँ इस बात पर निगरानी रखती हैं कि क्षेत्र-विशेष में किसी महाशक्ति द्वारा चुनौती प्रस्तुत की गई है या किसी अन्य राज्य द्वारा। जब चुनौती किसी महाशक्ति की ओर से नहीं आती तो दोनों ही महाशक्तियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से अथवा पदों के पीछे की कूटनीति से (Behind-the-scenes diplomacy) प्रायः परस्पर सहयोग करती हैं। जहाँ चुनौती दोनों में से किसी एक महाशक्ति द्वारा प्रस्तुत हुई हो, वहाँ प्रायः अवरोध (Deadlock) की स्थिति पैदा हो जाती है। बर्लिन, वियतनाम आदि के सन्दर्भ में इस प्रकार की अवरोधपूर्ण स्थितियाँ पैदा हो चुकी हैं। अन्य राज्यों द्वारा क्षेत्रीय प्रभुत्व के प्रयत्नों को रोकने में रूस-अमेरिकी सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक महत्वपूर्ण संस्थात्मक आधार-स्थल (An important institutional setting) के रूप में

काम किया है। दोनों महाशक्तियों ने किसी युद्ध-विराम को लागू करने के लिए कई बार महामन्त्रि के सद्-प्रयासों का स्वागत किया है। साद्व्यवस्था, मध्य-पूर्व और भारत-पाक संघर्षों में ऐसा हो चुका है। युद्ध के विस्तार की रोकने में कई अवसरों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ एक प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष सिद्ध हुआ है।

11. आज के विश्व में प्राकृतिक या संयोगवश पड़ित होने वाले प्राणविक युद्ध की सम्भावना बढ गई। यह स्थिति समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक गम्भीर चुनौती है।

12. दोनों ही महाशक्तियों की द्वितीय-प्राघातकारी क्षमता (The Second-Strike Capability) पहलकारी आक्रमणों पर एक निरोधक का काम करती है।

13. वर्तमान विश्व में यह खतरा बढ गया है कि कोई भी संघर्ष प्राणविक युद्ध में परिणत हो सकता है।

14. महाशक्तियों ने अपनी रणनीतियों और व्यूह-रचनाओं को उभर बनाने की नीति का अनुसरण किया है, लेकिन प्रत्यक्ष एक दूसरे से संघर्ष की नीति को सदैव टाला है। यह स्थिति वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखने में सहायक सिद्ध हुई है।

15. समकालीन विश्व में दो महायुद्धों के बीच की अवधि की तुलना में निःशस्त्रीकरण ने एक अधिक मध्यम प्रतिमान (A More Moderate Pattern) का अनुसरण किया है। द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में हम पर अधिक बल दिया जाने लगा है। अधिकांश समकालीन निरुपेक्षता निःशस्त्रीकरण को एक ऐसा मापन या उपाय मानने लगे हैं जो युद्ध के खतरे को कम करता है।

16. संयुक्त राष्ट्रसंघ ने राज्यों के बीच सम्पर्क के द्वार खुले रख कर और 'मौखिक संघर्ष' (Verbal Conflict) के सार्वजनिक मंच (A Public Forum) के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर बड़े पैमाने के युद्धों के खतरों को कम करने में प्रभावी भूमिका निभाई है।

17. यद्यपि कतिपय क्षेत्रों में कभी-कभी विश्व-साम्राज्य की चुनौती को एक 'सम्भावना' (Possibility) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन समकालीन विश्व की स्थितियों को देखते हुए यह एक बहुत दूर का स्वप्न है।

18. समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को मुख्य चुनौती व्यापक युद्धों और सैनिक-वृत्ति (Warfare) से है। इस प्रकार के युद्धों का होना यदि अनिवार्य नहीं है तो असम्भव भी नहीं है।

इस स्थिति में सुगमता से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ वास्तविक हैं। देशीय साम्राज्य, इधर-उधर भड़क उठने वाले व्यापक युद्ध, प्राकृतिक प्राणविक युद्ध का खतरा, राजनीतिक तनाव के बहुमुखी केन्द्र और इसी प्रकार की अन्य चुनौतियाँ व्यवस्था के सामने मौजूद हैं। निकट भविष्य में तो हम एक ऐसे ही विश्व में रहेंगे जिसमें प्राणविक युद्ध का खतरा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन का एक प्रमुख पक्ष

बना रहेगा और इस सन्दर्भ में उत्पन्न करने वाली स्थितियों में निश्चित ही हमारी योग्यता पर ही बहुत-बुद्ध यह निर्भर है कि समस्याओं में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहार क्या होगा या नहीं और यह मानव-क्रांति मजबूत होगी या विनष्ट।

अन्तर्राष्ट्रीय सौदेबाजी की प्रक्रिया में प्रवृत्तियाँ

(Trends in the International Bargaining Process)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के पूर्ववर्ती विवेचन के प्रसंग में अब हमें देवना चाहिए कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की नई दिशाएँ, उत्पन्न, प्रवृत्तियाँ आदि क्या हैं। अन्य दिशाओं और उत्पन्न की विवेचना में पूर्व संक्षेप हम उन प्रवृत्तियों पर दृष्टिमान करेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय सौदेबाजी की प्रक्रिया को प्रभावित किए हुए हैं। जिस तरह दूतावतदार और सौदेबाजी करते हैं, राज्यों में राजनीतिक नेताओं और राजनीतिज्ञों में चलते-चलते दिनों की गति तरङ्ग-तरङ्ग की सौदेबाजी होती है, उसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था पर राजनीतिक कार्यक्रमों या राज्य तरङ्ग-तरङ्ग की सौदेबाजी करते हैं। तथापि, जैसा कि विनियम कोषिका में दिया है, पुरातन युग की युवता में धात्र के युग में राज्यों के मध्य प्रतियोगितापूर्ण सौदेबाजी की क्षमता में काफी परिवर्तन आ गया है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था धात्र भी रही है जिसमें राज्य इस बात के निर्धारण के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं कि किसको क्या, क्या और कौन मिला, तथापि यह तरीके बदल गए हैं जिनमें वे एक दूसरे से प्रतियोगितापूर्ण सौदेबाजी करते हैं, और साथ ही बहुत से ऐसे मामले (Issues) भी बदल गए हैं जिन पर सौदेबाजी की जाती है।¹ इस दृष्टि में परिवर्तन के निम्नलिखित तीन क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

- (1) क्षेत्रीकरण
- (2) विवाद क्षेत्रों का विभाजन
- (3) शक्ति के प्रयोग में प्रवृत्तियाँ।

क्षेत्रीकरण (Regionalization)

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सौदेबाजी की प्रक्रिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्षेत्रीकरण की है अर्थात् सौदेबाजी के अनेक मामले केवल उन्हीं राज्यों से सम्बन्धित हैं जो एक क्षेत्र विशेष के हैं। क्षेत्रीकरण की इस स्थिति को हम 'क्षेत्रीय आधारों के अनुसूचित विभाजन' (Fragmentation Along Regional Lines) कह सकते हैं। पुरातन युग में यूरोपीय राज्यों की ही प्रमुखता थी। उदाहरणार्थ,

1 "The international political system continues to be a system in which states compete with each other in order to determine who gets what, when and how with only minor influence from international institutions. Even so, the ways in which they competitively bargain with each other and the classical issues over which they bargain have changed radically since the classical period."

—William D. Coplin : Introduction to International Politics, Second Edition, 1914, p. 368.

17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 'उत्तरी अमेरिका की राजनीति' यथार्थतः यूरोपीय राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ही एक भग थी और अमेरिका का जो स्वाधीनता-संग्राम लड़ा वह भी यूरोपीय राजनीति की ही उपज (Product) था।

चिन्तु आज हम भौगोलिक क्षेत्रों की 'राजनीति' की बात सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम पश्चिमी यूरोप की राजनीति, पूर्वी यूरोप की राजनीति, मध्य यूरोप की राजनीति या सेंट्रल अमेरिका की राजनीति की चर्चा करते हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र सौदेबाजी का एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जिसमें उस क्षेत्र के राज्य विभिन्न मसलों पर एक-दूसरे से सौदेबाजी करते हैं। यद्यपि वे राज्य दूर-दूर क्षेत्रों के राज्यों से भी कुछ मामलों पर सौदेबाजी में उलझे रहते हैं, तथापि यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि भौगोलिक क्षेत्र-विशेष के मसलों पर उस क्षेत्र के राज्य सौदेबाजी में अधिकाधिक लिप्त हों, सौदेबाजी की अन्त क्रियाओं (Interactions) का प्रसार हो। सौदेबाजी के क्षेत्रीय विभाजन (Regional Fragmentation of Bargaining) की यह प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के सार्वभौमिकरण (Universalization) का एक स्वाभाविक परिणाम या विकास है।¹ आज विश्व में 150 से भी अधिक राज्य हैं और भौगोलिक दशाओं में अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रों के राज्यों के हितों को पूर्वापेक्षा अधिक धनियता के साथ धावद करने की प्रवृत्ति है जिसके फलस्वरूप वे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिनसे सौदेबाजी की स्थितियों को प्रोत्साहन मिलता है।

क्षेत्रीकरण की प्रवृत्ति का एक प्रमुख परिणाम यह देखने को मिलता है कि क्षेत्रीय अन्तर्सरकारी संगठनों (Regional Inter-governmental Organizations) का काफी विकास हुआ है। अफ्रीकी एकता संगठन (The Organization of African Unity), अमेरिकी राज्यों का संगठन (The Organization of American States), अरब लीग (The Arab League), यूरोपीय परिषद् (The Council of Europe) आदि ऐसे ही क्षेत्रीय अन्तर्सरकारी संगठन हैं, जो एक ऐसा रगमंच प्रदान करते हैं जिस पर उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों की राजनीति का नाटक खेला जा सके। और तो और, समुक्त राष्ट्रसंघ जैसे विश्व-व्यापी अन्तर्सरकारी संगठन (Global Inter-governmental Organization) का क्षेत्रीय विभाजन पर अस्पष्ट प्रभाव (An Ambiguous Impact on Fragmentation) दिखाई देता है। एक ओर तो ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्सरकारी संगठन ससार भर में राज्यों को एक-दूसरे के निकट लाने और क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर आकर अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर सहयोगिता-पूर्ण सौदेबाजी के लिए प्रेरित करते हैं तो दूसरी ओर यह प्रवृत्ति भी दिखाई देती है कि एक क्षेत्र-विशेष के राज्य एकजुट होकर समुक्त राष्ट्रसंघ में मतदान करते हैं और इस प्रकार अपने क्षेत्र का प्रभाव दिखाने को उत्तुंग रहते हैं।

1 "This trend toward regional fragmentation of bargaining is a natural outgrowth of the universalization of the international political system."

—William D. Cohan : Ibid, p. 369.

अन्तर्राष्ट्रीय मौदेबाजी की प्रक्रिया के क्षेत्रीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम सम्भवतः यह हुआ है कि अनेक राज्यों को ऐसे बहुत कम अथवा प्रान्त होने हैं कि वे एक दूसरे में सीधे मौदेबाजी कर सकें। उदाहरणार्थ, गहारा प्रदेश के छोटे अफ्रीकी राज्य गैबो (Gabon, a Small Sub-Saharan African State) और मध्य अमेरिकी छोटा राज्य ग्वाटेमाला (Guatemala, a Small Central American State) में आपस में कोई नियमित झूटनीतिक सम्पर्क नहीं रहता और उन्हें एक-दूसरे में प्रायः मौदेबाजी का अथवा प्रायः नहीं मिलता, सिवाय इसके कि वे समुद्र-राष्ट्रमय जैसे विश्वव्यापी अन्तर्गमक संगठन में किसी किसी मौदेबाजी की स्थिति में आ सकते हैं।

विवाद-क्षेत्रों का विभाजन (Fragmentation of Issue Areas)

यदि हम समकालीन और पुरातन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना करें तो एक मुख्य अन्तर यह दिखाई देगा कि उन विवाद-क्षेत्रों की संख्या और विविधता बढ़ती जा रही है जिन पर राज्य परस्पर मौदेबाजी करते हैं। पुरातन युग में राज्य मुख्यतः उन क्षेत्र के नियन्त्रण पर मौदेबाजी करते थे जो उनकी भौगोलिक सुरक्षा में सम्बन्धित होता था। किन्तु समकालीन राज्य एक दूसरे में व्यापक और विविध विवाद-क्षेत्रों पर मौदेबाजी करते हैं जिनमें से अनेक का प्रादेशिक नियन्त्रण जैसे प्रश्नों में कोई सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरणार्थ, राज्यों के बीच अन्तर्गमक संगठनों के निर्माण और कार्य-समाप आर्थिक विकास की नीतियाँ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान, आदि प्रश्नों पर मौदेबाजी होती है। यहाँ तक कि कुछ राज्यों की आन्तरिक सामाजिक नीतियों (जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद नीति) पर भी राज्यों के मध्य मौदेबाजी होती है। जो प्रश्न प्रादेशिक नियन्त्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा में सम्बन्धित हैं उन पर मौदेबाजी की स्थितियाँ अधिक पेचीदा बन गई हैं। उदाहरणार्थ, गुटिय नीति (Alliance Policy) के सम्बन्ध में कोई समझौता केवल हिन्दी प्रादेशिक सदस्यों को लेकर ही नहीं किया जाता या किसी समझौते का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होता कि एक राज्य या राज्यों के गुट-विशेष से सुरक्षा की जानी है, बल्कि उस समझौते में और भी व्यापक हित-प्रश्न सम्मिलित होते हैं। नाटो, वारसा पंचक आदि संगठन केवल प्रादेशिक नियन्त्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्नों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि प्रतिबद्धताओं (Extensive Commitments) से बंधे हुए हैं जिनसे अनेक प्रकार की समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं जैसे विदेशी सेनाओं की तैनाती (Stationing of Foreign Troops), प्रशासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति (Appointment of Administrative Personnel), आधार-स्थलों की स्थिति (Location of Bases), सप्लाय-सदस्यों के समर्थकों का आवंटन (Allocation of Support from Alliance Members), आदि। राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति (National Security Politics) से शस्त्र-नियन्त्रण और निःशस्त्रीकरण जैसा विवाद-क्षेत्र या मसला (Issue Area) उत्पन्न हुआ है और आज 20वीं शताब्दी की विदेश नीति में यह

मसला अधिकारिक विवादस्पद बनता जा रहा है। विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद इस बात के प्रयासों ने जोर पकड़ा है कि आधुनिक सैनिक तकनीक के कुछ पहलुओं पर नियन्त्रण स्थापित किया जाए। पुनश्च, अन्तर्गत्तरी सगठनों के विकास ने भी विवाद-क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई है। उदाहरण के लिए, इन सगठनों की राजनीति के प्रश्न जिनमें सांविधानिक परिवर्तन, पदाधिसारियों के चुनाव, दण्ड सम्बन्धी आवंटन, सगठनों में राज्यों की स्थिति आदि शामिल हैं। राज्यों की विदेश-नीति के नए विवाद-क्षेत्र बन गए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्तर्गत्तरी सगठन मानव-अधिकारों, साम्यवाद बनाम पूँजीवाद, उपनिवेशवाद बनाम उपनिवेशवाद-विरोधी आदि मसलों पर मौखिक संधर्ष का रंगमंच प्रदान करते हैं। विवाद-क्षेत्र-विभाजन (Issue Area Fragmentation) का ही एक प्रभाव इस बात में दिखाई देता है कि राज्यों के भीतर विदेश-नीति-निर्माण प्रक्रिया का बड़ता हुआ विशेषीकरण और विभाजन (Growing Specialization and Fragmentation of the Foreign Policy making Process within States) हो रहा है। विवाद-क्षेत्रों का ही एक अन्य पहलू यह है कि कुछ विवादों पर दो राज्य परस्पर विरोध और शत्रुतापूर्ण रस अपनाते हैं जबकि दूसरे कुछ मसलों पर इन्हीं दो राज्यों में सहयोग होता है। जिस प्रकार घरेलू समाजों में राजनीतिक कार्यकर्ता प्रायः निरन्तर संधर्षरत रहते हैं वैसे राज्यों के मन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नहीं होना, अर्थात् राज्य निरन्तर पूर्ण संधर्ष में लीन नहीं रहते बल्कि पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों को ढूँढ निकालते हैं और इन हित-क्षेत्रों पर आपस में सौदेबाजी की व्यूह-रचना करते हैं।

शक्ति के प्रयोग में प्रवृत्तियाँ (Trends in the Use of Force)

पुरातन युग में युद्ध (Warfare) ही राज्यों के मध्य विवादों में अन्तिम मध्यस्थ या निर्णायक (A Final Arbiter) की भूमिका अदा करता था। "युद्ध एक न्यायालय अथवा व्यवस्थापन विभाग के समान कार्य करना था अर्थात् एक निर्णायकारी संस्था के रूप में था जो यह निर्धारित करता था कि किन राज्यों के हिसाब में क्या प्राय है। यद्यपि आज की भाँति ही चुनौतियाँ देने और हिसाब-किताब (Pay offs) को बदल देने के लिए शक्ति का प्रयोग भी होता था, तथापि युद्ध ही अन्तिम निर्णायक था अर्थात् यह निश्चित करने के लिए कि सौदेबाजी करने वाले राज्यों में जीत किस की हुई, लड़ाई लड़नी पड़ती थी।"।¹ उस समय की तकनीकी दशाएँ (Technological Conditions) ऐसी थी कि राजनीतिक रूप से यह सम्भव था कि जीते हुए भूखण्ड पर अधिकार बनाए रखा जाए। इसी तरह उस समय की राजनीतिक दशाएँ ऐसी थी कि विदेश नीति के निर्णायकर्ता किसी छोटे भू-क्षेत्र को

1 "War functional like a court or a legislature does—as a decision-making institution determining which states received what pay-offs. Although force was also used, is to-day, to communicate threats and to change pay-offs, war functioned as 'trial by combat'—that is, a fight to determine, not who was right, but who won what the states were bargaining over."

वास्तव में समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सौदेबाजी की प्रक्रिया में राज्य एक दूसरे के मामलों में इतने विविध और व्यापक क्षेत्रों में फँस गए हैं कि उनके लिए एक दूसरे को चुनौती देने या नुकसान पहुँचाने का प्रयास एक दूसरे की महायन्त्रा करने के लिए खुला और समृद्ध क्षेत्र है। अब यह उन पर, विशेषकर बड़े राज्यों पर निर्भर है कि वे सहयोग के क्षेत्र को बढ़ाकर मानवता को निरन्तर प्रगति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करते हैं या तनाव का प्रयास सधर के क्षेत्र बढ़ाकर मानवता को विनाश के कगार पर पहुँचाते हैं।

वर्तमान विश्व राजनीति के अन्य परिवर्तनशील तत्त्व एवं नई दिशाएँ तथा उत्तमर्ण (Other Dynamic Elements of Contemporary World Politics and New Dimensions and Tensions)

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर जिन युग का मूत्रपात हुआ उसमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार-क्षेत्र में अनेक 'नूतन क्षितिज' उभरे हैं, प्रभुत्व-क्षेत्र बदल गए हैं, नवीन प्रवृत्तियों और सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ है, अन्तर्राष्ट्रीय जगत् को नवीन समस्याएँ सताने लगी हैं, विदेश नीतियों के चेहरे बदलते जा रहे हैं—मतीप में विश्व-राजनीति का ताना-बाना महान् परिवर्तनों के दौर में गुजर चुका है और गुजरता जा रहा है। अनेक प्रवृत्तियों और पहलुओं का वर्णन पूर्व पृष्ठों में किया जा चुका है। कतिपय अन्य प्रमुख मोड़ और उत्तमर्ण जिनकी जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के उस व्यावहारिक पक्ष के लिए भी पृष्ठभूमि का काम करेंगी जिनका विवेचन पुस्तक के कुछ अन्तिम अध्यायों में किया गया है, इस प्रकार है—

1. विचारधाराओं का परिवर्तित रूप

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक रोचक पक्ष है कि साम्यवाद और पूँजीवाद—इन दो परम्परागत और परस्पर घोर विरोधी विचारधाराओं में जहाँ सधर शिथिल पड़ रहा है और इन विचारधाराओं के प्रतिपादक राष्ट्र एक दूसरे के निकट आकर सह-अस्तित्व की बात करने लगे हैं, वहाँ एक ही विचारधारा के बीच विभाजन की छाई चोड़ी हो रही है और उसके प्रतिपादक एक दूसरे की पूर्ण शक्ती की दृष्टि से देखते हुए पारस्परिक युद्ध तक की नौबत से आशंकित हैं। जो साम्यवादी राष्ट्र, रूस और चीन, पूँजीवादी देशों को बर्दाश्त करने को भी तैयार न थे और अमेरिकी नेतृत्व के पूँजीवादी खेमे को अपना सर्वोपरि शत्रु मानकर उसके उन्मूलन को प्राणपण से तत्पर थे, वे ही राष्ट्र अब पूँजीवाद के साथ सह-अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं। जो अमेरिका साम्यवादी चीन से बेमनस्य और शत्रुता को अपनी विदेश नीति की आधारशिला बनाए हुए था, वही अब उसकी घोर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इस प्रकार कल के शत्रु आज के मित्र बनने लगे हैं और जो विचारधारों हरे क्षण परस्पर टकराव की स्थिति में थी, वे अब सह-अस्तित्व की ओर उन्मुख हैं। दूसरी ओर एक ही विचारधारा और खेमे के दो राज्य रूस और

चीन एक दूसरे में आगति है। मार्क्स के दो बड़े मार्क्सवाद की अपनी-अपनी व्याख्या करने हुए एक दूसरे पर कीबड़ उठाते रहे हैं। मार्क्सवादी चीन की शिन्धारखाओ आजादीवादी ने मोक्सियन रुम की चीन में मोन दो है और उमें बाप्य होकर चीन से लगनी हुई चीन की मोना पर विशाल मंन्य शक्ति मयोजित करनी पड़ी है ताकि रही चीन उम इतिहास को न दोहरा दे जो 1962 में वह अपने अनिष्ट मित्र देन भारत के विश्व प्रसट पर चुका है।

2 बहुकेन्द्रवाद की ओर प्रवृत्ति

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् बहुकेन्द्रवाद (Polycentrism) की ओर उन्मुख है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में द्विध्रुवीयता (Bi-Polarity) का अर्थ है विश्व का दो शक्ति-मुटो या केन्द्रों में विभाजित हो जाना और बहुकेन्द्रवाद का अर्थ है शक्ति के अनेक केन्द्रों का उदय हो जाना। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त मयुक्त राज्य अमेरिका और मोक्सियन रुम के नेतृत्व में दो शक्ति मुटो का तेजी से उदय हुआ, पर 1960 के आते-आते इन द्विध्रुवीयता के बन्धन निधिल पड़ने लगे और विश्व जर्न-जर्न बहुकेन्द्रवाद की ओर अग्रसर होने लगा। सबसे पहले द्विध्रुवीयता को राष्ट्रीयता की शक्तियों ने चुनोती दी। एशिया और अफ्रीका के नवजागरण ने दो-दो मुटो में घुपक रहने की नीति अपनाकर द्विकेन्द्रित व्यवस्था को ओर अधिपति निधिल बनाया। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने अदा की। इनके अनिरुक्त पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपने आर्थिक पुनर्निर्माण द्वारा स्वयं को पुन शक्ति सम्पन्न कर यह साहा कि अब वे अमेरिका के विरुद्ध खनकर नहीं रहेंगे। विशेषकर फ्रांस ने स्वर्गीय जनरल डिगाल के नेतृत्व में विश्व की द्विध्रुवीय व्यवस्था को विशेष आघात पहुँचाया। इस व्यवस्था को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में इस बात ने भी आघात पहुँचा कि अशु-आसुधों का एकाधिकार अमेरिका और रुम के पास से गिम्बने लगा तथा ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी अशु-शक्ति सम्पन्न बन गए।

नवोदित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रूपरेखा यद्यपि अभी मुस्पष्ट और मुनिश्चित नहीं है, तथापि दो शक्ति-मुटो की जगह अधिक शक्ति-केन्द्र साफ तौर पर उभर आए हैं। एशिया में भारत और चीन की उपेक्षा करना अब विश्व की दो महाशक्तियों, रुम और अमेरिका के लिए सम्भव नहीं है तो पश्चिमेशिया में इजराइल और मिस्र प्रमुख शक्ति केन्द्रों के रूप में उभरे हैं—यद्यपि यद्यप्य रूप में वे क्षेत्रीय शक्ति-केन्द्र ही हैं।

वस्तुतः वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहुकेन्द्रीय है जिसमें केवल पूँजीवादी, मार्क्सवादी और तटस्थतावादी खेमे ही नहीं हैं बल्कि अन्य राष्ट्र और मयुक्त राष्ट्रमण भी सम्मिलित हैं। आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी है कि मोके पर कमजोर में कमजोर राष्ट्र की आवाज भी अपना महत्व रखती है। इजराइल और मिस्र अपने खंदे में परिवर्तन द्वारा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को और महाशक्तियों के आसनी सम्बन्धों को भवभोर करते हैं। शक्ति-मन्तुलन की ऐतिहासिक परम्परा का आज विशेष महत्व नहीं रह गया है और सामूहिक-सुरक्षा व्यवस्था की बात

अव्यावहारिक प्रतीत होने लगी है। वर्तमान के आधार पर यही प्रतीत होना है कि भविष्य में अभी अनेक महत्वपूर्ण शक्ति-केन्द्रों का उदय होना बाकी है।

3. क्षेत्रीय संगठनों के रूप और प्रकृति में अन्तर

क्षेत्रीय संगठनों (Regional Organizations) का आधारभूत तत्त्व राष्ट्रों की सुरक्षा था और यह धारणा की गई थी कि ये संगठन किसी भी सदस्य-राष्ट्र पर विदेशी आक्रमण होने की दशा में आक्रमणकारी का विरोध मिलकर करेंगे, किन्तु आज की बदली हुई परिस्थितियों में क्षेत्रीय संगठनों पर किंग सीमा तक निर्भर रखा जा सकता है, यह 1965 और 1971 में भारत-पाक युद्धों से स्पष्ट हो चुका है। नाटो और सैंटो के बल पर कूदने वाले पाकिस्तान को इन संगठनों से किन्ती निराशा हाथ लगी होगी, इसका सही अनुमान तो वह युद्ध ही लगा सकता है। पुनश्च, आज की तेजी में बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ये मैग्न-संगठन पहले के समान महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। एक तो पहले के शत्रु-राष्ट्र अब एक दूसरे के निकट आने लगे हैं और दूसरे, संगठनों के सदस्य-राष्ट्र उन देशों के साथ मैत्री स्थापित करके, जिनके विरुद्ध संगठनों का निर्माण किया गया है, संगठनों में दरार डाल चुके हैं। तीसरे, कुछ सैन्य-संगठनों द्वारा मध्य-राष्ट्रों को साम्यवाद का प्रतिरोध करने के लिए जो हथियार दिए जाते हैं उनका प्रयोग साम्यवाद के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रजातन्त्र के विरुद्ध किया जाने लगा है। चौथे, यह भय बहुत प्रबल है कि आज के आणविक युग में इन संगठनों द्वारा की गई जरा सी भूल अथवा विस्फोटक कार्यवाही महाविनाशक युद्ध में परिणत हो सकती है। मक्षेप में, क्षेत्रीय संगठनों के रूप और उनकी प्रकृति में अन्तर आ गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति परिवर्तित दृष्टिकोण के अनुरूप प्रभावित होने लगी है।

4. विभिन्न देशों के स्तरों में परिवर्तन

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आज यूरोपीय देशों की राजनीति ही नहीं रह गई है। एशिया और अफ्रीका का नवजागरण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नए महत्व, नए सम्बन्ध और नए प्रभाव का सूचक है। आज अफ्रीकाई राष्ट्रों का भाव्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ बंधा हुआ नहीं है, अब वे अपनी स्वतन्त्र विदेश-नीति का प्रयोग करने लगे हैं और संयुक्त राष्ट्रसंघ में उनकी आवाज की उपेक्षा करना किसी भी महाशक्ति के लिए सुगम नहीं है। इन राष्ट्रों के निर्णयों का आधुनिक विश्व-राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत और चीन नई महाशक्तियों के रूप में उदित हो रहे हैं और अपने सिद्धान्तों के अनुरूप विश्व-राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं। भारत एशिया में लोकतन्त्र का गढ़ है और उसके भविष्य पर समूचे विश्व के लोकतन्त्र का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है तो चीन प्रादेशिक विस्तारवादी, सैन्यवादी तथा कुटिल राजनीति का खिलाड़ी है जो विश्व की सभी लोकतान्त्रिक शक्तियों के लिए चुभती है। इसीलिए आज इतना शक्ति सम्पन्न बन चुका है कि अरब राष्ट्र उसके अस्तित्व को अनचाहे भी स्वीकार करने को बाध्य है। पाकिस्तान सैनिक तानाशाही के अधीन अपने ही हाथों अपने पैरो कुल्हाड़ी मार कर विखण्डित हो

ही चुका है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पारितोषिक मानक तानाशाही के नियन्त्रण में बार-बार पोंग जाता है।

ध्यान दे यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति जगत् में विभिन्न देशों के मनो में कभी मन्यर मति में तो कभी मोत्री के परिवर्तन आते जा रहे हैं, उनकी विदेश-नीतिशील नए रूप धारण कर रही है और यह सब घटनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को जटिल से जटिलतर बना रहा है।

5. विश्व-मस्या के प्रति परिवर्तित रूप

विश्व-मस्या, मयुक्त राष्ट्रमण्डल के प्रति मगार के राष्ट्रों का एक मात्र उतना उत्साहप्रद नहीं है जितना इस समस्या की स्थापना के समय मौजूद था। अधिकांश राष्ट्र इसके निष्ठान्तों के प्रति समुचित रूप से निष्ठावान नहीं हैं और सुरक्षा-समिति महाशक्तियों के हाथों का गिलोता बनी हुई है। मयुक्त राष्ट्रमण्डल ने मकलना या तो उन मामलों में कोई है जिनमें महाशक्तियों में इन्ने पूरा सहयोग मिला अथवा उन छोटे छोटे और कम महत्व के विवादों में जिनमें महाशक्तियाँ प्रत्यक्ष सम्बन्धित नहीं थी और जिनमें उनके हितों की टकराव नहीं थी। अब अब अधिकांश देशों में यह दृष्टिकोण बन पकड़ने लगा है कि मयुक्त राष्ट्रमण्डल ईमानदारी में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। बलाशक्ति के स्वाधीनता-मण्डप के दौरान पारितोषिक के बर्बर अत्याचारों के प्रति मयुक्त राष्ट्रमण्डल ने जो निष्क्रियता प्रदर्शित की, उसने इस समस्या में शान्तिप्रिय राष्ट्रों की धारणा को भस्मोदित दिया है। साम्यवादी चीन के प्रवेश में विश्व-मस्या की महत्त्वता व्यापक हुई है, लेकिन चीन का दृष्टिकोण इस समस्या को बही तक रक्षणात्मक शक्ति दे सकेगा, यह संदेहास्पद है। इजरायल और अरब-राष्ट्र मयुक्त राष्ट्रमण्डल की नीति-नीति में ऊब चुके हैं और मध्य-पूर्व अथवा पश्चिमी एशिया के मकल के समाधान में विश्व-मस्या में कोई विशेष धारणा नहीं की जा सकती। विपतनाम-युद्ध में भी, जो अब सम्बन्धित राष्ट्रों की प्रत्यक्ष वार्ता के कारण समाप्त हो चुका है, इस समस्या की प्रथमता ही प्रदर्शित हुई है।

अभिप्राय यह है कि मयुक्त राष्ट्रमण्डल के प्रति मद्भावना और सक्रिय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रों का उदासीन एक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् में विन्ता का विषय है। हेनरी स्पाक के चेतावनी भरे ये शब्द भुलाए नहीं जा सकते कि "हमें अपने देश के हितों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, लेकिन हमें तब तक मकलना नहीं मिल सकेगी जब तक अपने देश के हितों को हम सामान्य हितों की दृष्टि से नहीं देखेंगे और विश्व तथा मानव-हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे।" इस स्पष्ट कथन में कोई अनिश्चयता नहीं है कि "हम आदर्शवाद की भोक में चाहे कितने ही मुभाव दें, लेकिन यथार्थ स्थिति यही है कि यदि सदस्य-राष्ट्र और विशेषकर महान् राष्ट्र सहयोग से कार्य नहीं करेंगे तो मयुक्त राष्ट्रमण्डल अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रमण्डल की भाँति ही नष्ट हो जाएगा।" यह चिन्ताजनक बात है कि ऐसे राष्ट्रों की संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही है जो विश्व-मस्या द्वारा अपनी समस्या को हल करने की अपेक्षा शक्ति प्रयोग द्वारा गुलामाना अधिक उचित समझते हैं।

6. अणुशक्ति के नए स्वामी

हेनरी एल. रॉबर्ट्स ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचाने वाली सबसे बड़ी समस्याएँ हैं 'अणु' और सम्पूर्णतावाद। अणु-शक्ति का निरन्तर विस्तार होने के साथ-साथ इनसे प्रभावित राजनीति अपना रंग ला रही है। अणु-शक्ति के विकास के मूल में दो दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं—

प्रथम, भारत, कनाडा जैसे देश अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग की विचारधारा को बल प्रदान कर रहे हैं, एवं

द्वितीय, अमेरिका, चीन आदि राष्ट्रों में अणुशक्ति सम्पूर्णतावादी विचारधारा को बल प्रदान कर रही है।

शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति के विकास पर जो राष्ट्र जोर भरा रहे हैं, यह एक समझ में न आने वाली बात है विशेषकर उस सूरत में जबकि वे राष्ट्र स्वयं आणविक शस्त्रास्त्रों के भण्डार खड़े कर रहे हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम में कहीं भी आक्रमणकारी विचार के चिन्ह तक नहीं है। 18 मई 1974 को पश्चिमी राजस्थान में भारत का पहला नाभिकीय विस्फोट अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण विकास और अनुसंधान का प्रतीक था किन्तु अमेरिका जैसी महाशक्ति ने आशंका प्रकट कर दी कि भारत के परमाणु विस्फोट से विश्व में स्थायित्व को धक्का पहुँचेगा। अमेरिका स्वयं यह भूल गया कि वह अणु शक्ति के प्रसार में स्वयं बितने जो-जान से लगा है। यह वह भी भूल गया कि आणविक युद्ध का आरम्भ करके लाखों व्यक्तियों की खून की होती सबसे पहले 1945 में उसी ने खेली थी। भारत के विरुद्ध शत्रुता रखने वाले चीन, पाकिस्तान जैसे देशों का विरोध तो स्वाभाविक ही था, पर कनाडा, जापान आदि देशों ने भी जो विरोध किया उसके मूल में सम्भवतः किरोध कम था, गलतफहमी अधिक थी। और अब जबकि पाकिस्तान परमाणु विस्फोट की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, तो अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र चुपों साधे हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में इस प्रकार का मन व्याप्त है कि पाकिस्तान को अनेक विशिष्ट क्षेत्रों से इस दिशा में पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है।

विश्व की समूची वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि अणुशक्ति के विनाशकारी विकास की अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है और कुछ राष्ट्रों में सम्पूर्णतावादी विचारधारा बहुत जोर पकड़ रही है। अमेरिका तो धीरे-विघ्नकारी न्यूट्रान बमों के निर्माण की योजना पर अपनी सम्पूर्ण शक्ति से धमल करने लगा है। वस्तुतः विनाश के लिए अणु शक्ति के विकास ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अनेक समस्याओं को अधिक जटिल बना दिया है और इन खतरों के बीच आज की किरण यही है कि सहस्रान्तित्व और समझौतावादी प्रवृत्ति भी पनपी है। प्रलयकारी आधुनिक के रहते हुए आज कोई भी राष्ट्र यथार्थता महायुद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। जो महाशक्तियाँ

घातविक शस्त्रास्त्रों के भण्डारों की स्वामी हैं वे भी यह समझने लगी हैं कि युद्ध के क्षेत्र को अधिकाधिक सीमित रखने और अणुशस्त्रों के प्रयोग को टालने में ही उनका मुद्दा का भवा है। अणुशक्ति के मयस्वर गठ ने ही अमेरिका और रूस तथा चीन और अमेरिका को परस्पर निश्चिन्त घातों के लिए बाध्य किया है तथा अणुशक्ति-सम्पन्न चीनी अजगर की कुत्तार में अन्त सोवियत रूस ने भारत की मंत्री का और भारत ने रूसी मंत्री का महत्व समझा है। सारांश में, अणुशक्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अणुशून्य और प्रतिशून्य दोनों ही रूपों में प्रभावित कर रही है।

7. शीत-युद्ध

युद्धात्तर युग में महाशक्तियों के मध्य में एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को जन्म दिया है जो 'शीत-युद्ध' (Cold War) के नाम से विख्यात है। इस स्थिति में विरोधी राष्ट्रों में यद्यपि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहते हैं और प्रत्यक्ष शत्रुता नहीं होती, तथापि उनका पारस्परिक व्यवहार शत्रुवत् रहता है। अमेरिका रूस-चीन और उनके विद्यमान राष्ट्रों के बीच जो तीव्र शीत-युद्ध रहा, वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभी भी प्रबुद्ध पाठक के लिए एक गुणग्वित तथ्य है। शीत-युद्ध ने ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अत्यन्त मोर्चे मुखरान है। उदाहरणार्थ, पश्चिमी शक्तियों ने नाटों की स्थापना की तो रूस ने वारसा पेश किया। बोरियाई युद्ध के समय शीत-युद्ध ने ऊष्ण ध्रुवों में महाशक्तियों की विदेश नीति को प्रभावित किया। शीत-युद्ध के तनावों को कम करने के लिए शीत युद्ध के नेताओं के शिखर सम्मेलन हुए और समानानुसार विदेश नीति को उभय तथा नरम बनाया जाता रहा। मयूक्त राष्ट्रसंघ के मंच पर विश्व राष्ट्रों ने जो भूमिकाएँ घटा की उन पर शीत-युद्ध के उतार-चढ़ाव का गहरा स्पष्ट प्रभाव रहा। सोवियत-अमेरिका संमनस्य और शीत-युद्ध ने विश्व के राष्ट्रों को तेजी में दो गेमों में विभाजित कर दिया और उनसे उत्पन्न परिस्थितियों ने मुक्त-निरपेक्षता की विदेश नीति को प्रोत्साहन दिया। दो गेमों की टक्कर को रोकने और दोनों के बीच पुल का काम करने के लिए अमनस्यता की विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकाधिक स-मान मिलता गया। पश्चात्य शक्तियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच शीत-युद्ध की छाया प्रज्ज्वलित रखी जिससे दोनों देशों के बीच अनेक युद्ध हुए। पाकिस्तान की विदेश नीति में मौनिक मुद्दबन्दी का तत्व सर्वोपरि रहा और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की सीमा पर मौनिक तयारियाँ करनी पड़ी। शीत-युद्ध के असाहे ने ही महाशक्तियों को पश्चिमी एशिया, विद्यमान, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका में एक दूसरे के सामने ताल ठोकने को विवश किया है। यह शीत-युद्ध न चले तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सहयोग और सह-अस्तित्व की दिशा में दौड़ पड़ेगी, इसमें सन्देह नहीं। पिछले कुछ वर्षों में शीत-युद्ध पिछले दौर की तुलना में बहुत कुछ शांत रहा है, तथापि 1981 के अन्तिम चरण से कुछ घटनाओं के कारण इसे पुनः खल मिला है, यथा: दिसम्बर, 1981 में पोलैण्ड में तथाकथित सोवियत हस्तक्षेप और अमेरिका द्वारा पोल्स्का तथा सोवियत संघ के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध, अमेरिका

द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 विमान देने सम्बन्धी निर्णय, 15 दिसम्बर, 1981 को इजरायल द्वारा गोलान पहाड़ियों पर विधिवत् कब्जा करने का फैसला आदि ।

8. मध्यपूर्व और सुदूरपूर्व की विशिष्ट स्थिति

महायुद्ध के उपरान्त एशिया के दो प्रदेश मध्यपूर्व और सुदूरपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में निरन्तर विशेष महत्व प्राप्त करते गए और आज भी ये विश्व का प्रधान संकटस्थल (Danger spots) बने हुए हैं । मध्यपूर्व तेल के वृहत् भण्डारों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रावर्ण्य केन्द्र है तो भारत और सात चीन के उदय ने सुदूरपूर्व के प्रदेश को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदेशों की श्रेणी में ला दिया है । वास्तव में एशिया द्वितीय महायुद्ध के बाद में ही विश्व-राजनीति का तूफान केन्द्र (Storm centre) बना हुआ है । शान्ति की शक्तियाँ प्रयत्न करती हैं, सन्ध के बादल कुछ भ्रमों के लिए छट जाते हैं और फिर पुनः धूम पड़ने हैं । इजरायल और अरब राष्ट्रों की शत्रुता, अरब राष्ट्रों का पारस्परिक वैमनस्य, ईरान-इराक संघर्ष आदि ने मध्य पूर्व को एक 'विस्फोटक केन्द्र' की स्थिति प्रदान की । इधर भारत के प्रति पाकिस्तान, चीन और बंगलादेश के रवैये को मित्रतापूर्ण नहीं कहा जा सकता । तथापि यह बात उत्साहवर्धक है कि भारत और चीन के बीच वार्ता के द्वार पुनः खुले हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच भनाप्रमाण मधि की दिशा में 1981 के अन्तिम चरण से बातचीत चली है और बंगलादेश के साथ भी तनाव के बिन्दु कुछ कम हुए हैं । भारत उत्तरोत्तर अधिक और सैनिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र बनता जा रहा है और उसकी स्थिति को अनदेखी करना किसी भी महाशक्ति लिये 'आत्मघातक' होगा ।

9. साम्राज्यवाद का बदलता हुआ स्वरूप

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नई विस्फोटक प्रवृत्ति यह है कि साम्राज्यवाद के नए परिवर्तन में उभरने के आसार नजर आ रहे हैं । प्रादेशिक साम्राज्यवाद तो अस्तान्त की ओर है, लेकिन अधिक और राजनीति साम्राज्यवाद पर पसाग्ने के लिए प्रयत्नशील है । जून, 1976 में इस्ताम्बुल (भारत) में 'अफ्रीका दिवस समारोह' में साम्राज्यवाद के इस नए रूप का पर्दाफाश करते हुए ठीक ही कहा गया था "विश्व के सभी अविक्सित देशों की जनता का संघर्ष एक-सा है । उनकी समस्याएँ एक-सी हैं । सभी अविक्सित देशों का शत्रु बढ़ता हुआ साम्राज्यवाद है जो दूसरे महायुद्ध के बाद अनेक नए रूपों में अविक्सित देशों का शोषण कर रहा है । यह सही है कि आज साम्राज्यवाद का रूप वह नहीं है जो आज से पचास वर्ष पहले था, लेकिन आज नव साम्राज्यवाद का जो रूप है वह भयानक है । इसमें रूप-भेद भले ही हो, शोषण-भेद नहीं है । साम्राज्यवाद के इस नए रूप को समाप्त करने के लिए सभी अविक्सित देशों की जनता को एक जुट होकर संघर्ष करना चाहिए सभी एक तीसरे विश्व की कल्पना सार्यक होगी ।" अफ्रीका इस नए साम्राज्यवाद का विशेष स्थल है, लेकिन अफ्रीकी जनता अब जाग उठी है और विभिन्न प्रकार से साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोर्चा ले रही है । यह संघर्ष जहाँ एक ओर जन-आन्दोलनों

के रूप में है, यही दूसरी ओर इनके साथ बुद्धिजीवियों का आन्दोलन भी इस मुक्ति लक्ष्य को तीव्र और स्थायी बनाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है और बौद्धिक तथा वैचारिक स्तर पर नई दुनिया का सूत्रपात कर रहा है। यह एक शुभ संकेत है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

10. युद्धोपरान्त विश्व में समायोग

युद्धोपरान्त के विश्व में शान्तिपूर्ण समायोग की समस्या (Problem of Peaceful Co-existence) अनेक कारणों से महत्वपूर्ण बन चुकी है। प्रथम, परमाणु शक्तों के विभाग से युद्ध-मानवता के लिए बहुत भारी गहरा बन चुका है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था कि शान्तिपूर्ण समायोग का स्वभाव विरल्य गायुहिक विनाश ही है। द्वितीय, इस समय साम्यवादी और पूंजीवादी राष्ट्रों के गुट आपस में घोर संतिर शक्ति में इनके समान रूप में गन्तुवित है कि कोई भी आने वाले वर्षे बाल तक के लिए एक दूसरे को हारने की आशा नहीं कर सकता। यह उचित भय है कि तीव्र विश्व युद्ध इतना सभ्य होगा कि इसके भयानक परिणामों और प्रभावों का इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।¹

संयुक्त राज्य और सोवियत संघ की युद्धोपरान्त नीतियों का मूल्यांकन प्यानपूर्वक किया जाए तो पता चलता है कि दोनों देशों की सरकारों ने विश्व राजनीति में इनके विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान रखा है कि समय के साथ इन दोनों प्रणालियों में शान्तिपूर्ण समायोग की सम्भावना और भी अधिक बल होती जा रही है। किसी भी पक्ष की प्रगति करने या आरोप लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष ही हीन युद्ध की नीतियों की किरा और प्रतिप्रियाओं के चक्कर में अत्यधिक फँस चुके हैं।² तथापि यह भी स्वीकार करना होगा कि शक्ति केन्द्रों के विस्तार, सैनिक शक्ति के गन्तुवन, परमाणु युद्ध के अन्तिम विनाश के भय आदि के कारण शान्तिपूर्ण समायोग की संभावनाओं को बल मिला है। यह आवश्यक है कि शान्तिपूर्ण समायोग की इच्छा के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों को शान्तिपूर्वक सुलभने के वास्तविक प्रयत्न भी होने चाहिए। प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष की विचारधारा के साथ बही समायोजन करना पड़ेगा तभी सामान्य समझौते की स्थिति हो सकती है। हम और संयुक्त राज्य में शान्तिपूर्ण समायोग तभी हो सकता है जब वे पारस्परिक भयों को वार्तालाप और मध्यस्थता द्वारा सुलभ कर सकें।³

11. गुटनिरपेक्ष देशों को उत्तरोत्तर बढ़ती भूमिका

गुटनिरपेक्षता आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना प्रभावी होता जा रहा है कि महाशक्तियों और विश्व के पूंजीवादी तथा साम्यवादी सेमों द्वारा गुटनिरपेक्ष देशों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। मिनम्बर, 1961 के वेतघेड गुटनिरपेक्ष प्रथम शिखर सम्मेलन में केवल 5 देश ही शामिल हुए थे जबकि सितम्बर, 1979 के हवाना शिखर सम्मेलन में 94 देश शामिल हुए जिसमें 20 देश

और संगठन प्रेषक थे तथा 18 देश प्रतिधि थे। समय के साथ गुट-निरपेक्षता का रूप निखरता जा रहा है और अधिक वास्तविक होता जा रहा है। प्रारम्भ में इसकी नीति आवश्यकता से अधिक आदर्शवादी थी, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं ने गुट-निरपेक्ष देशों को यह अनुभव करा दिया कि इस नीति को अधिक यथार्थवादी बनाया जाए, और राष्ट्रीय हित के तत्व को प्रधानता दी जाए। भारत ने इस नीति को परिष्कृत करने तथा इसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हाल ही के वर्षों में गुट-निरपेक्षता की नीति में पारस्परिक आर्थिक सहयोग के तत्व पर विशेष बल दिया जाने लगा है। राजनीतिक पहलू की तुलना में आर्थिक पहलू पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिए जाने से गुट-निरपेक्षता की धारणा की सार्वकता सिद्ध हुई है। गुट-निरपेक्षता का परस्पर विरोधी स्वरूप भी अस्तित्व में है जिसका स्पष्ट उदाहरण पश्चिमेशिया में दृष्टिगोचर होता है। कतिपय अरब राष्ट्रों के सोवियत मध्य के साथ अत्यधिक बंध जाने से गुट-निरपेक्षता की शका की दृष्टि से देखा जा रहा है तथापि इस तथ्य की मुलायमा नहीं जाना चाहिए कि अरब राष्ट्र अपनी राजनीतिज्ञ प्रगुना पर कोई प्रांच न माने देने के प्रति सचेत हैं। वास्तव में पश्चिमेशिया का क्षेत्र एक तरह से सचेत और सावधान गुटबन्दी का अखाड़ा बन गया है।

12. सम्प्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त, उपनिवेशवाद का लोप होने के साथ-साथ, सम्प्रभु राज्यों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जहाँ 1955 में संयुक्त राष्ट्रमध्य के सदस्यों की संख्या केवल 51 थी वहाँ 1982 के प्रारम्भ में यह 156 थी। 26 सितम्बर, 1981 को बेलीज संयुक्त राष्ट्र का 156वां सदस्य स्वीकार किया गया था। सम्प्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप बहुत-कुछ बदल गया है और विभिन्न राज्यों के स्तरों तथा स्थितियों में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। अफेसियाई राष्ट्रों की भावाज विश्व-मध्या में आज अधिक बुलन्द है।

अन्य उलभनें

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की और भी अनेक उलभनें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रभावित कर रही हैं। ये उलभनें सैद्धान्तिक भी है और व्यावहारिक भी। एक बड़ी उलभन यह है कि राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के बीच सघर्षों की एक शृंखला सी बन गई है। इन दोनों के बीच समायोजन करना है। दूसरा तनाव राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच समुचित सामञ्जस्य सम्बन्धी है। जब तक राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था राजनीतिक संगठन का मुख्य रूप है, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा को ही प्रधानता मिलेगी। दोनों के बीच सघर्ष अनिवार्य नहीं है क्योंकि एक को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों को अपनाया जाता है, वे कभी-कभी दूसरे को प्राप्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। पर दोनों

के मध्य टकराहट का क्षेत्र भी कम नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की तीव्र गति के अन्तर्गत उसका महयोग और मर्त्य के मापेक्षित महत्त्व की है। दोनों ही प्रवृत्तियों के उदाहरण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् में उपस्थित होने रहते हैं जिनसे ज्ञानि तथा मुक्त जंगी मूल समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पर रचनात्मक पहलू ही मानवता का संरक्षक है और इंगीनिष् मर्त्य की अपेक्षा महयोग अधिक सामान्य है तथा इसे प्रोत्साहित करने की दिशा में समानांतर प्रयास किए जाते हैं। चौथी उपभन्ध यह है कि एक ओर तो संभव की घटनेवियाँ हैं और दूसरी ओर निर्धनता का ताण्डव नृत्य है। एक ओर वैज्ञानिक प्रगति तथा तकनीकी विकास ने धरती पर स्वर्ग उतार दिया है और दूसरी ओर ज्ञान-विज्ञान तथा माधनों के पिछड़ेपन ने मानव-मन्यता के बहुत से क्षेत्रों में हम धरती को नर्क बना रखा है। ये दोनों ही स्थितियाँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को गम्भीर रूप में प्रभावित किए हैं। विकासशील, अविश्विष्ट और विकास राष्ट्रों की राजनीति अणु-अणुता सेल, सेल रही है और विश्व-राजनीति के नाटक को रचनात्मक और विध्वंसात्मक अभिनयों में पूर्ण बना रही है। पाँचवी उपभन्ध सौरतान्त्रिक और प्रतिक्रियात्मक शक्तियों का मर्त्य है। रणभेद की नीति तो मानव-अधिकारी पर तमाचा है ही, असीरीकरण जंगी महत्त्व विश्व-राजनीति को और भी विषाक्त बना रही है, यह छात्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गम्भीर समस्या बन चुकी है। छठा विरोधाभास यह है कि एक ओर तो मानव-इतिहास में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव बन्धन के प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी ओर प्रतिक्रियावाद के नाम पर सामूहिक हत्याओं, अत्याचार और अमानवीय परिस्थितियों का जोर बढ़ रहा है। समता के प्रयत्नों की तुलना में विषमताएँ इतनी बढ़ रही हैं कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से विश्व राजनीति के कार्य-कर्ताओं के लिए वे गिरदर्द हैं।

इन विभिन्न उपभन्धों, विरोधाभासों और तनावों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अस्त है तथा निरवर्त समस्याएँ उठ रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्निहितों को इनका समाधान करना है और इसकी सकलता पर ही मानव जाति का भविष्य निर्भर करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मुक्ति-संघर्ष (Freedom Struggles in International Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्त्वपूर्ण आधुनिक पक्ष मुक्ति-संघर्षों की स्वायत्तता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता-केन्द्रों की चर्चा में इस घटना की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। कोई भी सत्ता-केन्द्र स्वतन्त्र रूप से राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम होता है और राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम भी वह शक्तिशाली घटक है जिसमें स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने की ताकत सन्निहित है। विषयनाम-मुक्त, बंगलादेश संघर्ष, आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चीनविद् गोविन्द पुरुषोत्तम देशपाण्डे ने लिखा है—
“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन एक स्वतन्त्र घटक है। इसका

तात्पर्य क्या है ? इस घटक की स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति कितनी है ? सत्ता-केन्द्र गुट या कि सत्तात्रय (अर्थात् अमेरिका, सोवियत रूस और चीन) एक होकर भी क्या मुक्ति-संग्राम को रोक सकते हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर पर आगे वाले कुछ वर्षों में एशियायी राजनीति का भविष्य अवलम्बित रहेगा ।"

हम देख चुके हैं कि वियतनाम-युद्ध ने सर्वशक्ति सम्पन्न अमेरिका तक को नाकों घने बना दिए । लगभग 149 लाख डॉलर तक में मिलाकर और एक लाख के आस-पास अमेरिकियों को जान गवां कर भी आखिर अमेरिका को क्या हासिल हुआ ? बंगलादेश के मुक्ति-संग्राम को कुचल देने के पाकिस्तानी प्रयासों या क्या परिणाम निकला ? इन सबका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष "किमी के द्वारा न तोड़ी जा सकने वाली ऐसी राजनीय और सैनिक शक्ति का निर्माण कर लेता है कि उसकी ताकत से टक्कर लेना सहज नहीं होता ।" आज वस्तुतः राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम की स्वायत्तता स्पष्ट हो गई है और राम तौर पर एशियायी राजनीति के बारे में विचार करते समय तो इस तत्व के महत्व को हम उपेक्षा नहीं कर सकते । श्री देशपाण्डे का वह अभिमत संबंध ठीक है कि "कठिनाइयों से उत्पन्न होने वाला यह आत्म-विश्वास और आन्तरिक बल (मुक्ति-संघर्ष) यदि ध्यान में न रखा जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर किया गया कोई भी विचार भ्रमुरा रहेगा । एशियायी राजनीति में सही जोश की राष्ट्रवादी शक्ति मुक्ति-संग्राम से सम्बन्धित है । चीन का उदय भी राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष का ही परिणाम था और अब वियतनाम यदि खड़ा होगा तो इसी मुक्ति-संग्राम के बल पर ।"

अपने विश्लेषण में श्री देशपाण्डे ने आगे लिखा है कि "अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य संघर्ष के घटक महाशक्ति और छोटी शक्ति ही होते हैं । राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण अस्त्र होता है । इसके मुकाबले में अभी तक तो अन्य किसी प्रभावकारी अस्त्र का निर्माण नहीं हो पाया है और जब तक ऐसा न हो पाए तब तक मुक्ति-संघर्षों का महत्व हमें अपने सामने रखना ही होगा, नहीं तो जाने-अनजाने हमारे कदम इतिहास की धारा के विपरीत चलने लगेंगे ।"



अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त : विभिन्न दृष्टिकोण

(Theories of International Politics:
Different Approaches)

“सिद्धान्त का निर्णय किसी पूर्व-निश्चित, निगूढ़ एवं अवास्तविक विचार से नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसके उद्देश्य से ही इसका निर्णय होना चाहिए।”
—हंस जे. मॉर्गेंथो

द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अधिकाधिक वैज्ञानिक बनता जा रहा है और विद्वानों ने इसके कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी किया है। हंस जे मॉर्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धान्त (Realistic Theory) तो इतना महत्वपूर्ण है कि उसे भली-भाँति समझे बिना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का गुचाह रूप से अध्ययन करना कठिन है।

किसी भी विषय के समुचित अध्ययन और गवेषण में सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि सिद्धान्त कुछ सामान्य नियमों का एक ऐसा मुख्यवर्धन समूह होता है जिनके आधार पर घटनाओं और क्रिया-कलापों का गहन एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है। सिद्धान्त के अन्तर्गत जो नियम गठित होते हैं, वे प्रमुख परिस्थितियों और घटनाओं से उत्पन्न प्रश्नों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। सिद्धान्त वे साधन हैं जो हर कार्य और घटना से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों—क्या, क्यों और कैसे—का कुछ न कुछ उत्तर प्रस्तुत करते हैं।¹ इनके आधार पर हम अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ पाते हैं और सम्बन्धित नीतियाँ निर्धारित कर सकते हैं। आशय यह है कि सिद्धान्त केवल अध्ययन का साधन ही नहीं होते, बल्कि नीति-निर्माण में भी हमारा पथ-प्रदर्शन करते हैं। यदि हम उन सिद्धान्तों को समझ लें जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में प्रतिपादित किए गए हैं तो विषय-सामग्री के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही पक्षों को समझने

1 *Stainley H. Hoffmann (ed.) : Contemporary Theory in International Relations, pp. 29-54.*

में सहायता मिलती है। प्रस्तुत अध्याय में यद्यपि हमारा मन्तव्य मुख्य रूप से यथार्थवादी सिद्धान्त का अध्ययन है, तथापि कतिपय अन्य सिद्धान्तों और सम्बन्धित बातों का संक्षिप्त विस्तार भी अपेक्षित है।

विभिन्न दृष्टिकोण (Different Approaches)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन सम्बन्धी जो विभिन्न दृष्टिकोण प्रकट किए जाते रहे हैं, उन्हें सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है—

- (1) ऐतिहासिक दृष्टिकोण (Historical Approach)
- (2) यथार्थवादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण
(Realistic and Idealistic Approach)
- (3) समन्वयवादी दृष्टिकोण (Eclectic Approach)
- (4) व्यवस्थावादी दृष्टिकोण (System Approach)
- (5) नीति-विज्ञानवादी दृष्टिकोण (Policy-Science Approach)

(1) ऐतिहासिक दृष्टिकोण (Historical Approach)

यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक मुख्य परम्परावादी दृष्टिकोण है जो इतिहास को एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखता है जिनमें वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विश्लेषण एवं परीक्षण होता रहता है। अतीत की आधारभूत पर वर्तमान का निर्माण किया जाता रहा है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ अतीत की परम्पराओं और विचारों से बड़ी गीमा तक प्रभावित हुई हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वर्तमान परिस्थितियों से भावी घटनाओं का स्वरूप बहुत-कुछ निर्धारित होता है। मूल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर विकास का श्रम सदैव विद्यमान रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार परिवर्तन और विकास का नियम सदैव अस्तित्व में रहता है, अतः नीतियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित एवं स्थायी दिशानिर्देश न तो उपयुक्त ही है और न समुचित रूप से सम्भव ही। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनयिक इतिहास (Diplomatic History) का अध्ययन अत्यावश्यक है क्योंकि कुशल राजनय के बल पर, चाहे उसका स्वरूप द्विपक्षीय हो अथवा बहुपक्षीय, हम समस्याओं का उपयुक्त समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक उपयुक्त और शक्तिशाली पक्ष प्रस्तुत करता है, तथापि यह अपूर्ण एवं अपर्याप्त है। पेंडेलफोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में, “वर्तमान युग में केवल राजनीतिक इतिहास का अध्ययन लाभप्रद होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। आज राजनीति शास्त्र के अध्येता के लिए अतीत के इतिहास से प्राप्त जानकारी की अपेक्षा वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में नीति-निर्धारण-प्रक्रिया तथा राजनीतिक सौदेबाजी की कला का ज्ञान कहीं अधिक आवश्यक है।” यह आलोचना बहुत-कुछ बजन रखती है, इससे इन्कार नहीं

किया जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा अन्य किसी भी विषय के सांगोपांग अध्ययन में हम इतिहास की पूर्ण अपेक्षा नहीं कर सकते, पर साथ ही उस पर ही पूरी तरह निर्भर करना भी एकपक्षीय तथा हानिकारक होगा। ब्रिटेन और वहाँ की निशा प्रणाली से प्रभावित बहुत से देशों में द्वितीय महायुद्ध से कुछ वर्षों बाद तक इतिहासवादी दृष्टिकोण काफी प्रभावशाली रहा, लेकिन ज्यों-ज्यों नीति-युद्ध की उन्नता बढ़ती गई और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की यथार्थता उजागर होती गई, इतिहासवादी दृष्टिकोण की सीमात्रियता घटती गई। आज के प्रचलित मन्दमं में यह दृष्टिकोण पुरातन, परम्परावादी और धिमापिटा माना जाता है जो हमें अध्ययन की गहराई तक नहीं पहुँचाना, घटनाओं के अनेक वास्तविक और प्रभावशाली तत्वों पर प्रकाश नहीं डालता। फिर भी जहाँ तक अपने अध्ययन और विश्लेषण में इतिहास का सहारा अपेक्षित है, वहाँ तक इसकी उपयोगिता टूट-साई भी नहीं जा सकती।

(2) राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद (Political Realism and Political Idealism)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में प्रमुख टक्कर यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोणों की है। ये दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन का गहो और मुद्दक गिढ़ान्न होने का दावा करते हैं। जार्ज केनन तथा हंम मॉर्गन्थो समकालीन यथार्थवादियों में सबसे प्रमुख हैं। वाल्टरस, लॉगवेल, ईस्टन आदि ने भी यथार्थवादी दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया है। आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ताओं में बुट्टरे विल्सन, बर्ट्रण्ड रसेल आदि हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद अनुभव और तर्कों पर आधारित है जिसमें तथ्यों तथा घटनाओं के वास्तविक स्वरूप के अध्ययन के उपरान्त तर्कमग्न निष्कर्ष निकाले जाने पर आग्रह है। यह दृष्टिकोण सुरक्षा और शक्ति तत्वों के निहितार्थों (Implications of Security and Power Factors) पर विचार करता है।¹ इस प्रकार के विचार व्यक्ति के ऐसे विश्वासों के परिणाम होते हैं कि दूसरे लोग उसे सदा नष्ट करने की किराक में रहते हैं, अतः अपनी सुरक्षा की खातिर उसे दूसरों को मार डालने के लिए सदैव सजग और तत्पर रहना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण में यह विचार निहित है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में संघर्ष, संघर्ष आदि मौजूद रहता है अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय समाज में शक्ति अथवा प्रभाव की प्रतिस्पर्धा सदैव चलती रहती है और किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा सरकार द्वारा इस प्रतिस्पर्धा या संघर्षात्मक स्थिति को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता अतः कूटनीति और राजनीतिज्ञता का प्रमुख कार्य यही है कि शक्ति-प्रतिस्पर्धा पर किसी न किसी रूप में झुंझ लगाया जाए और इस प्रकार के साधनों का सहारा लिया जाए कि यथासाध्य संघर्ष का विस्फोट न हो पाए। शक्तिस्पर्धा पर झुंझ रखने के लिए अपनाए जाने

वाले इस प्रकार के साधन वास्तव में 'नया शक्ति-सन्तुलन' (A new balance of power) है। यथार्थवाद शक्ति-समर्पण के स्थायित्व को स्वीकार करता है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। वास्तविक उदात्त और अमूर्त मान्यताओं के स्थान पर यह दृष्टिकोण इस वास्तविकता में विश्वास करता है कि यह सत्ता विभिन्न परस्पर-विरोधी हितों और स्वार्थों का रंगमंच है जो आपस में टकराने रहते हैं, अतः किन्हीं नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर हम किसी समर्पण-रहित आदर्श अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते और उपयुक्त यही है कि विभिन्न विरोधी स्वार्थों के मध्य सन्तुलन की स्थापना द्वारा समर्पण को टालते रहने का प्रयत्न किया जाए। इस बहुलवादी समाज पर अवरोध और सन्तुलन का सिद्धान्त ही लागू किया जा सकता है।

जॉर्ज केनन और हम मॉर्गेंथो दोनों ही इस विश्वास को आधार मानकर चले हैं कि राष्ट्रीय हित ही किसी भी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति तथा विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण के लिए अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय हित तथा नैतिक सिद्धान्तों के बीच सम्बन्ध की प्रकृति का प्रश्न है, दोनों ही विचारकों के मत एक-दूसरे में भिन्न हैं। जॉर्ज केनन के अनुसार हम केवल अपने ही हितों को जानें और समझ सकते हैं तथा कोई भी समाज दूसरों की घरेलू समस्याओं और आवश्यकताओं का निर्णायक नहीं हो सकता।¹ अतः उचित यही है कि एक ओर तो हम अपने राष्ट्रीय हितों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी विदेश-नीति और वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन का प्रयास करें और दूसरी ओर उन नैतिक तथा आदर्श सिद्धान्तों के अनुसरण का भी प्रयास करें जो हमारी सभ्यता में अन्तर्निहित हैं। पर इस प्रकार के नैतिक और आदर्श सिद्धान्त केवल हमारे अपने लिए ही वैध प्रयोज्य मान्य हो सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं, और इसीलिए हमें दूसरों पर इन सिद्धान्तों को थोपने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जॉर्ज केनन के इन विचारों के विपरीत हम मॉर्गेंथो ने राष्ट्रीय हित की सर्वोच्चता की वकालत की है और यह सुनिश्चित विचार प्रकट किया है कि नैतिकता के सभी सिद्धान्त राष्ट्रीय हित की बलिबेदी पर चढ़ाए जा सकते हैं। मॉर्गेंथो के यथार्थवादी दृष्टिकोण का विवेचन पृष्ठ 6 से इसी अध्याय में आगे किया गया है। यहाँ इतना ही निश्चय पर्याप्त है कि यथार्थवादियों में इस बात पर वास्तविक मतभेद नहीं पाया जाता कि राष्ट्रीय हित को किसी सीमा तक प्रमुखता दी जानी चाहिए। इस बात पर अवश्य ही उनमें सहमति है कि हमारी विदेश-नीति और वैदेशिक सम्बन्धों का मार्गदर्शक राष्ट्रीय हित है न कि नैतिक सिद्धान्त।

यथार्थवादियों के विपरीत आदर्शवादी शक्ति-राजनीति (Power-politics) को इतिहास तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अस्थायी पक्ष मानते हैं। उनके मतानुसार यथार्थवाद एक ऐसी अवधारणा है जो इतिहास के वास्तविक अर्थ को

सोडमी-मरोहनी तथा भष्ट करती है। आदर्शवाद समाज के अमित्र विभाग में विखराग करता है। इस दृष्टिकोण का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था और अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रान्तियों के पीछे यह प्रेरणा का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। प्रारम्भिक आदर्श विचारों में कोंडोरसेट (Condorcet) का नाम उल्लेखनीय है जिसने सन् 1795 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में एक ऐसी आदर्श विश्व-व्यवस्था की कल्पना प्रस्तुत की है जिसमें युद्ध, विषमता और अत्याचार का सर्वथा अभाव हो तब विवेक, शिक्षा, विज्ञान आदि के माध्यम में मानव-सन्ध्या की अविराम धारा बहती रहे।

सार्वजनिक में आदर्शवाद भावी अन्तर्राष्ट्रीय समाज की यह तस्वीर गींचता है जो शक्ति-राजनीति, अनेकिकता, हिंसा आदि में मुक्त एक सुधरी हुई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विचार पर आधारित है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि समुचित जेदता तथा अन्तर्राष्ट्रीय गठन की प्रभावशाली सहायता से हम आज की अपेक्षा एक अधिक सुन्दर और अधिक अखण्ड समाज का निर्माण कर सकते हैं। उनका तर्क है कि अतीत में जो राजनीतिक संघर्ष हुए वे शक्ति अथवा प्रभाव के लिए नहीं हुए थे, बल्कि वे परस्पर विरोधी आदर्शों और सिद्धान्तों के बीच होने वाले संघर्ष थे। आदर्शवादियों में भी जो स्वप्नदर्शी हैं अर्थात् कल्पनालोक में अधिक उड़ान भरते हैं, उन्होंने शक्ति-राजनीति पर आधारित इस विश्व की विनाश में बचाने के लिए तीन मार्ग सुझाए हैं—(1) नैतिक राष्ट्रों को चाहिए कि वे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में परम्परागत शक्ति-नीति के स्थान पर सर्वत्र नैतिक सिद्धान्तों का अनुसरण करें, (2) सभी सम्भव उपायों में निरन्तर यह प्रयाग होना चाहिए कि सौजन्य-विरोधी मार्काधिरारवादी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो, एवं (3) एक विश्व-भरकार की स्थापना द्वारा शक्ति-राजनीति को समाप्त किया जाए। इस प्रकार कल्पनावादियों अथवा आदर्शवादियों का विश्वास है कि यदि एक विश्व अथवा विश्व-मध्याद के आदर्श की अंगना लिया जाए तो हम शक्ति-राजनीति के अधिशासकों में बच सकते हैं, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय जगत् का चित्र ही बदल सकते हैं।

राजनीति में यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद में परस्पर विरोध का सबसे बड़ा केन्द्र-बिन्दु शक्ति की समस्या है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान युग में प्रथम महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के स्व. राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में आदर्शवाद पर जोर दिया गया था और द्वितीय महायुद्धोत्तर अवधि में वुड्रो विल्सन के समकालीन सबसे बड़े प्रवक्ता रहे हैं। दो महायुद्धों के बीच के युग में यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच विरोध काफी झुल कर सामने आया। यथार्थवाद को राष्ट्रपिता और आदर्शवाद को अन्तर्राष्ट्रीयता से सम्बद्ध समझा गया और इस धारणा को बल मिला कि जहाँ यथार्थवादी नीतियाँ शान्ति-विरोधी हैं तथा राष्ट्रीय शक्ति के प्रसार को अंगना लक्ष्य मानती हैं, वहीं आदर्शवादी नीतियाँ शान्ति को प्रोत्साहित करने वाली हैं।

यद्यपि उद्धृत प्रकार के विवेचन को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता और यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप का बहुत अधिक सरलीकरण है, तथापि इसमें

कोई सन्देह नहीं कि यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच संघर्ष का मुख्य कारण यही है कि यथार्थवादी यह पूर्ण निश्चय नहीं कर सके हैं कि शक्ति की दौड़ (Pursuit of Power) एक लक्ष्य है अथवा साधन। एक ओर तो उन्होंने शक्ति को यह सर्वोच्च मूल्य माना है जिसकी प्राप्ति के लिए राज्य को प्रयत्नशील होना चाहिए, दूसरी ओर शक्ति को साधन के रूप में भी देखा है। अनेक विद्वानों का तर्क है कि चूंकि मूल्यों की खोज (Pursuit of Values) सामान्यतया आदर्शवाद से सम्बन्धित है अतः हम यथार्थवाद को भी उस सीमा तक आदर्शवादी जामा पहना सकते हैं जहाँ तक वह मूल्यों की खोज पर बल देता है, पर दोनों में बड़ा भारी अन्तर यह है कि जहाँ आदर्शवाद उन मूल्यों पर आधारित है जो दार्शनिक दृष्टि से ठोस हैं और प्राथमिक महत्व के हैं वहाँ आदर्शवाद शक्ति की प्राथमिकता से शुरु होता है और अन्त में इसे एक मूल्य के स्तर तक ऊँचा उठा देता है ताकि इस आधारित का निराकरण किया जा सके कि यह सिद्धान्त मूल्य-रहित (Valueless) है। चूंकि यथार्थवाद भी मूल्यों की भूमिका को स्वीकार करता है, अतः स्पष्ट है कि हम किन्हीं भी सामाजिक और राजनीतिक मामलों में मूल्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद में विरोध अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिकता और मानदण्डों के सम्बन्धों के प्रश्न को प्रभावित करता है।

ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर हम यही पाएंगे कि राजनीति का प्रत्येक रूप और स्तर, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी सम्मिलित है, नैतिकता की समस्या (Problem of Ethics) से भ्रूणित नहीं है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं हो सकता जो किसी न किसी रूप में और किसी न किसी मात्रा तक नैतिक पहलू से असम्बद्ध हो। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इस स्थिति को राइनहोल्ड नीबूर, हर्बर्ट बटरफील्ड, ई. एच. कार आदि विद्वान् बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। विद्वानों ने अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के काम से कम तीन पहलुओं का स्पष्ट रूप से संकेत किया है—प्रथम, राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों के लिए प्रयत्न करना चाहिए; द्वितीय राष्ट्रों को अपने हितों में सामञ्जस्य लाने के साधन और उपाय खोजने का प्रयत्न करना चाहिए; एवं तृतीय, अत्याचार का विरोध करना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में जिन नैतिक तत्वों की चर्चा ऊपर की गई है उनसे स्पष्ट है कि राजनीतिक आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रीय हितों में परस्पर ताल-मेल बँटाया जाना अपेक्षित भी है और सम्भव भी पर यह विचार यथार्थवादी दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। वस्तुतः ये दोनों ही दृष्टिकोण प्रतिवादी रस अपनाए हुए हैं, एक उत्तर की ओर जाता है तो दूसरा दक्षिण की ओर। उपर्युक्त यही है कि समय और आवश्यकता के अनुरूप दोनों दृष्टिकोणों की अच्छाईयों को ग्रहण किया जाए। राजनीतिक रूप से यह उपयुक्त है कि राष्ट्रीय हितों के अनुसार सफलतापूर्वक कार्य किया जाए, पर साथ ही राजनीतिक और नैतिक विवेक की माँग है कि यथासम्भव सर्वाधिक नैतिक मार्ग का भी इस ढंग से अनुसरण किया जाए कि आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नैतिकता-अनैतिकता के विवाद में न पौंगे बल्कि आधुनिक सनातनी के मुखिरान्ता दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल ने ठीक ही लिखा है कि आज लोगों के एक-दूसरे प्रति राजनीतिक व्यवहार पूर्णतः मूलतः आदशों पर आधारित है और उनके बचने के लिए हमें बिलकुल भिन्न आदशों पर आश्रय लेना होगा। हमें अनापश्यक प्रतिस्पर्धा, शक्ति-लातना और द्वेष को जन्म देने वाली अधिराज-निष्ठा के स्थान पर रचनात्मक प्रेरणाओं को अपनाना और विकसित करना होगा।¹ सभी विश्व के राष्ट्रों के बीच प्रेम और सहयोग का आनादरण बन गयेगा। रसेल ने चाहे एक स्थान पर विश्वास प्रकट किया है कि गुप्त और समृद्धि में परिपूर्ण विश्व का निर्माण कोई ऐसी बात नहीं है जो मानव-नैतिक से परे हो। अचेतन प्रकृति द्वारा जो बाधाएँ होती हैं उन पर तो विजय पायी हो जा सकती है, पर वास्तविक बाधाएँ तो मानव-मन में विद्यमान हैं और इनका निदान मुदिबान्ति दृष्टि आशा में ही मग्न है।²

(3) समन्वयवादी दृष्टिकोण (Eclectic Approach)

आदर्शवाद और यथार्थवाद के अतिवादी दृष्टिकोणों का परिणाम करते हुए दोनों के मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण करने वाला समन्वयवादी दृष्टिकोण है। यह यथार्थवाद की निराशा और आदर्शवाद की आशा में समन्वय स्थापित करता है। यह दोनों में से किसी भी दृष्टिकोण को पूर्णतः मनोपजनक नहीं मानता। समन्वयवाद का आग्रह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय पद्धति अपनाई जाए अर्थात् कोई पूर्वाग्रह या पूर्व-मान्यता न रखते हुए विश्व की राजनीतिक गतिविधियों का तटस्थ भाव से पर्यवेक्षण किया जाए और तथ्यों के संग्रह तथा विश्लेषण के मार्ग पर बढ़ा जाए। यह उचित नहीं है कि हम पहले किसी मिडान्त को निश्चित करें और तब उसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् की घटनाओं की व्याख्या करें। उपयुक्त मार्ग तो यह है कि हम विश्व घबरा अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की घटनाओं के विश्लेषण के माध्यम से किसी परिणाम तक पहुँचने का प्रयत्न करें। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक बहु-पक्षीय और निरन्तर गतिशील जटिल विषय है जिसे हम पहले से ही किसी एक मिडान्त की सीमा में नहीं बाँध सकते। विश्व-राजनीति की उलझी हुई परिस्थितियों के तथ्यात्मक (Factual) विश्लेषण द्वारा ही हम विषय-वस्तु को अधिक गहराई से समझ सकते हैं।

स्टैनले हॉकमैन, पेंडेसकोर्ड, जॉर्ज लिचन आदि विद्वान् समन्वयवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। स्टैनले हॉकमैन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इन चार घटकों अथवा तत्वों (Components) पर विशेष बल दिया है—(1) किसी समय विशेष में विश्व का राजनीतिक ढाँचा, (2) उस ढाँचे की इकाइयों अर्थात् राज्यों को प्रभावित

1 *Bertrand Russel : Political Ideals*, p. 9.

2 *Bertrand Russel : Roads to Freedom*, Ch. VI.

करने वाली आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियाँ, (3) राज्यों की गृह तथा विदेश नीतियों का परस्पर सम्बन्ध, एवं (4) इन सभी तत्वों के संयोग से प्रकट होने वाले राजनीतिक सम्बन्धों का तानाबाना। हॉफमैन की निश्चित धारणा है कि प्रथम तीन तत्वों की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं पर ही किसी समय विशेष में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का वास्तविक स्वरूप निर्भर रहता है। अतः अपेक्षित है कि इन प्रमुख तत्वों और अन्य सहयोगी उप-तत्वों तथा उनकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं का गहन अध्ययन कर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को समझा जाए और इस तथ्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से किनी परिणाम पर पहुँचने का प्रयत्न किया जाए। पैडेलफोर्ड एवं लिक्न का भी मत है कि यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का समुचित अध्ययन करना चाहते हैं तो उपयुक्त और व्यावहारिक तरीका यही है कि विभिन्न राज्यों की आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करने वाले तथा उनके माध्यम से विश्व-राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों-उपतत्वों को भव्यभूति जान लें और उनका सम्यक् विश्लेषण करें।

(4) व्यवस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण (System Approach)

इस दृष्टिकोण के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 'एक व्यवस्था' अथवा एक सुव्यवस्थित ढाँचा विद्यमान है जिसके विभिन्न अंग पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं द्वारा परस्पर सम्बन्ध स्थापित रखते हैं। विश्व की सभी राजनीतिक गतिविधियाँ इस सुव्यवस्थित ढाँचे के अंगों की इन्हीं आपसी क्रिया-प्रतिक्रियाओं का परिणाम हैं। आजकल 'व्यवस्था' शब्द तीन भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है—प्रथम अर्थ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक ढाँचा स्वयं तो निष्क्रिय है, किन्तु उसका गठन करने वाले अंग अर्थात् राज्य सक्रिय हैं जिनकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं द्वारा ढाँचे की आकार और गतिशीलता प्राप्त होती है, अतः ढाँचे की अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इसके प्रत्येक अंग के क्रियाकलापों को जानना आवश्यक है। द्वितीय अर्थ के अनुसार ढाँचा ही प्रधान है जो अपने विभिन्न अंगों की गतिविधियों तथा उनके कार्यकलापों को नियन्त्रित एवं उनके स्वरूप को निर्धारित करता है। तृतीय अर्थ के अनुसार 'व्यवस्था' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन एवं विश्लेषण की पद्धति-विशेष है। प्रो. गुडमैन के अनुसार 'व्यवस्था' के ये सभी अर्थ प्रचलित हैं। व्यवस्थापरक दृष्टिकोण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के सन्दर्भ में हमारे समक्ष कुछ उपयोगी प्रतिमान (Model) प्रस्तुत करता है और कुछ ऐसे नियम भी प्रस्तुत करने में समर्थ है जो हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भावी दिशा का कुछ आभास दे सकें।

अपनी विशिष्ट मान्यताओं के अनुरूप विद्वानों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन-क्षेत्र में अनेक व्यवस्थापरक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं जिनमें प्रमुख ये हैं—

- (1) शक्ति-सन्तुलन सम्बन्धी दृष्टिकोण (The Balance of Power System Approach)
- (2) साम्यावस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण (Equilibrium Approach)

(3) द्विध्रुवीय दृष्टिकोण (Bipolar System)

(4) विश्व-व्यापक सम्बन्धी दृष्टिकोण (Universal System Approach)

(5) मोर्टन काप्लान का छः व्यवस्थाओं सम्बन्धी दृष्टिकोण (Morton Kaplan's Six Systems Theory)

1. शक्ति सन्तुलन सम्बन्धी दृष्टिकोण (The Balance of Power System Approach) — यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो व्यवस्था घोर सम्बन्धना है वह शक्ति-सन्तुलन के कारण है। राष्ट्रीय शक्ति शिखी भी राज्य-व्यवस्था का मुख्य घन होती है, घन राष्ट्रीय हितों के संरक्षण एवं सम्बन्धों के लिए विभिन्न राज्यों के बीच स्पर्धाओं और गणनों का प्रतिफल रहता है। कोई एक राज्य अपना राज्य-समूह पराधीन शक्ति ग्रहण न कर ले, इसके लिए विभिन्न राष्ट्र संघों में जगह रहने हैं अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में समान्यता बनाए रखने के लिए शक्ति-सन्तुलन का निर्माण करते हैं। गत तीन शताब्दियों का सम्पूर्ण यूरोपीय राजनीतिक इतिहास शक्ति-सन्तुलन के बनने-बिगड़ने का इतिहास था और वर्तमान शताब्दी में भी शक्ति-सन्तुलन कायम रखने के लिए विभिन्न गणियों और समझौतों का साध्य विद्या जाता रहा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद शीत-युद्ध के मन्दर्भ में भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति-सन्तुलन की धारणा अपनी भूमिका खटा करती रही है। साम्यवादी शक्तियों के मुकाबले पश्चिमी राष्ट्रों ने अमेरिका के नेतृत्व में शक्ति-सन्तुलन कायम किया है। विभिन्न गैर-गणियों और प्रति-गणियों शक्ति-सन्तुलन कायम रखने के ही प्रयास हैं। एशिया और अफ्रीका के तटस्थतावादी राज्य भी शक्ति-सन्तुलन के मन्दर्भ में 'सन्तुलन' (Balancer) का कार्य कर रहे हैं। यह शक्ति-सन्तुलन कई प्रकार का हो सकता है—जैसे मध्यम एवं बड़े सन्तुलन; स्थानीय, क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी सन्तुलन; गरल एवं जटिल सन्तुलन। आज भी परिस्थितियों में विश्वव्यापी शक्ति-सन्तुलन का भार अमेरिका और सोवियत रूस के साथ-साथ साम्यवादी चीन और मोरक्कान्त्रि भारत पर भी धा गया है।

यद्यपि इतिहास शक्ति-सन्तुलन के दृष्टिकोण का समर्थन करता है और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी शक्ति-सन्तुलन की भूमिका स्पष्ट है, तथापि इसकी परम्परागत मान्यता में संदेह है। एक तो आज के लगभग 156 स्वतन्त्र राज्यों की पारस्परिक सांस्कृतिक विविधताएँ इतनी अधिक हैं कि उनमें वह राजनयिक निरटना सम्भव नहीं है जो यूरोपीय शक्ति-सन्तुलन के मन्दर्भ में थी, और दूसरे आज के धनु युग में इतने भयावह अस्त्र-शस्त्र बनाए जाने लगे हैं कि उनसे शक्ति-सन्तुलन सम्बन्धी व्यवस्था अपना धारणा पहले के समान प्रभावकारी नहीं रही है।

2. साम्यावस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण (Equilibrium Theory) — यह दृष्टिकोण शक्ति-सन्तुलन का ही एक अन्य रूप है जिसकी मान्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति सन्तुलन की ओर होती है अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में परस्पर-विरोधी शक्तियाँ एक-दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर किसी न किसी रूप में

स्थापित बनाए रखती हैं। इस साम्य-समस्या के दो रूप हैं—सामान्य (General) तथा संरचनात्मक (Constitutional)। सामान्य साम्यवाद-समस्या के समर्थकों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विभिन्न तत्वों में अर्थात् राज्यों, उनकी नीतियों, उनकी परिस्थितियों आदि में सन्तुलन की सहज प्रवृत्ति होती है। संरचनात्मक साम्यवाद-समस्या के समर्थकों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विभिन्न तत्वों में या तो साम्यवाद-पहले से ही मौजूद होती है अथवा उसे लाया जा सकता है। साम्यवाद-सिद्धान्त के एक मुख्य समर्थक जॉर्ज लिस्त के अनुसार प्राथमिक-मासिकृतिक एवं सामाजिक समुदाय, राजनीतिक-सामरिक क्षमता, व्यक्ति विशेष, आदि विभिन्न तत्व भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन के भ्रम हैं। अतः उन्होंने इसे 'बहुत साम्यवाद-समस्या' (Multiple Equilibrium) नाम देना उचित समझा है।

साम्यवाद-सिद्धान्त यद्यपि सन्तुलन में विश्वास प्रकट करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता कि सन्तुलन के लिए 'कितनी और कितनी शक्ति और प्रेरणा है' (How much more on which side)। शक्ति के निश्चित कार्य क्या हैं, यह भी इस दृष्टिकोण में स्पष्ट नहीं होता। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में इस सिद्धान्त की उपयोगिता केवल इतनी ही मानी जा सकती है कि यह एक व्यवस्था की ओर संकेत करता है।¹

3. द्विध्रुवीय दृष्टिकोण (Bipolar System)—इस दृष्टिकोण के अनुसार सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में शक्तिशाली और निर्णायक शक्तियाँ पूर्व तथा पश्चिम के दो शक्ति-केन्द्रों में अर्थात् साम्यवादों और साम्यवाद-विरोधी गुटों में विभाजित हैं। द्वितीय महायुद्ध काल में धुरी-राष्ट्रों (Axis Powers) और मित्र राष्ट्रों (Allied Powers) के रूप में द्विध्रुवत्व अथवा द्विकेन्द्रवाद स्पष्ट रूप में प्रकट हुआ और युद्धोत्तर युग में इसने साम्यवादों और साम्यवाद-विरोधी शक्तियों का रूप धारण कर लिया तथा इसका एक नया स्वरूप मांडल शीत-युद्ध के रूप में भी विकसित हुआ। यह द्विध्रुवीय दृष्टिकोण भी एक प्रकार का शक्ति-सन्तुलन सम्बन्धी दृष्टिकोण ही है। द्विध्रुवीय अवस्था कठोर (Tight) भी हो सकती है और शिथिल (Loose) भी। कठोर अवस्था में सभी राज्य स्पष्टतः किसी न किसी गुट अथवा शक्ति-केन्द्र से संलग्न रहते हैं और संकट के समय अपने गुट का पक्ष लेते हैं। शिथिल व्यवस्था में भी यद्यपि राष्ट्र गुटों में विभाजित रहते हैं किन्तु किन्हीं विशेष मामलों पर विरोधी गुट के साथ भी सहयोग करते हैं।

द्विध्रुवीय दृष्टिकोण भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक समुचित दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता विशेषकर वर्तमान सन्दर्भ में जबकि शक्ति के अनेक केन्द्रों का उदय हो रहा है अर्थात् बहुकेन्द्रवाद (Polycentrism) की ओर है। पृथक् राज्यों में परस्पर अथवा और सहयोगों का सिलसिला चलता रहता है,

1 Stanley Hoffmann : Contemporary Theory in International Relations, pp. 50-51.

उनके छापीली सम्बन्धों में प्रान्तिवादी परिवर्तन आने रहते हैं और इन सबके कारणों को हम द्विध्रुवीय व्यवस्था में नहीं ढूँढ़ सकते।

4. विश्व-व्यवस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण (Universal System Approach)—यह दृष्टिकोण आदर्शवाद का अनुसर जो सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार या समुदाय के रूप में मानता है और विभाजन करता है कि घनत्व-घनत्व राज्यों का अध्ययन न करके सम्पूर्ण मानव-जाति की समस्याओं के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। यह दृष्टिकोण राष्ट्रवाद का समर्थक है, घन. राज्यों की सम्प्रभुता को भीमिष अध्ययन समायोजन करके एक विश्वमंडल की स्थापना चाहता है। यह राज्यों की पृथक् सम्प्रभुताओं और राष्ट्रवाद को विश्व की सभी युगलों की जड़ मानता है। इसका तर्क है कि यदि माता अन्तर्राष्ट्रीय जगत् आतृष्ट्य के मूल में बँध जाएगा तो हमारी पेशानियाँ दूर हो जाएँगी।

यद्यपि यह दृष्टिकोण 'बहुध्रुवीय-वृद्धि' के महान् आदर्श में अनुप्राणित है, तथापि धात्र की जटिल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में विशेषकर सम्प्रभु राज्यों की महत्वाकांक्षाओं के प्रकाश में, यह आदर्श कभी पूरा हो सकेगा इसमें पूरा संदेह है। विश्व-शासन, विश्व व्यापक संगठन, समुक्त राष्ट्रमण आदि को इस दृष्टिकोण की विजय स्वीकार किया जाता है, पर विश्वमण (World Federation) जैसे आदर्श को प्राप्त हो सकेगी, यह सम्भव दिनाई नहीं देता। इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि इसमें मानव-मनोविज्ञान तथा विश्व को प्रभावित करने वाले समाजशास्त्रीय तत्वों की उपेक्षा करके कल्पना की उड़ान भरी गई है।

5. काप्लान का छः व्यवस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण (Morton Kaplan's Six Systems Theory)—मरचनारनक मनुनन को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विश्लेषण का आधार मानते हुए मार्टन काप्लान का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जम और सम्बद्धता है तथा आगे भी रहेगी। काप्लान ने अपनी माध्यता में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था दोनों को सम्मिलित किया है। उनका ध्यान है कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्यों ने सदैव अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है और भविष्य में भी निभाते रहेंगे, तथापि यह भूमिका समय और परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है। काप्लान का विचार है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को गुणवत्ता रखने के लिए भौतिक शक्ति (Physical Force) आवश्यक है। उनका विश्वास है कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, तथापि यह कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णयकर्त्ताओं की भूमिका राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका के अधीनस्थ होत, है। काप्लान का विश्वास है कि राष्ट्रीय राज्यों (National Actors) का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार सदैव राष्ट्रीय हित के आधारभूत विचारों से अनुप्राणित होता है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया

है—राष्ट्रीय राज्य (National Actors) तथा राष्ट्रोपरि राज्य (Super-national Actors)। संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्राँस और इटली यदि राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के उदाहरण हैं तो नाटो (NATO) राष्ट्रोपरि कार्यकर्ताओं का उदाहरण है। काप्लान के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय त्रिप्राकृताप अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच घटित होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं को काप्लान ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तत्व (Elements) माना है। समुचित अध्ययन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव की परीक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं के व्यवहार की परीक्षा भी आवश्यक है।

उपर्युक्त दार्शनिक भूमि के आधार पर काप्लान ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के लिए छ प्रकार की व्यवस्थाएँ सुझाई हैं—

- (1) शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था (The Balance of Power System)
- (2) शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था (The Loose Bipolar System)
- (3) कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था (The Tight Bipolar System)
- (4) सार्वभौम राज्य-व्यवस्था (The Universal Actor System)
- (5) श्रेणीबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (The Hierarchical International System)
- (6) इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था (The Unit Veto System)

काप्लान के अनुसार इन विभिन्न व्यवस्थाओं के गम्भीर अध्ययन के आधार पर हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के भूत, भावी और वर्तमान स्वरूप का समुचित विवेचन कर सकते हैं। ये सभी व्यवस्थाएँ काप्लान के प्रक्रिया-निकाय सिद्धान्त (Process System Theory) के प्रतिरूप हैं। उसने इन व्यवस्थाओं अथवा प्रतिरूपों की जो व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं उनसे इनकी परस्पर सम्बद्धता स्पष्ट होती है।

काप्लान के अनुसार प्रथम राष्ट्रीय-राज्य-व्यवस्था के साथ-साथ तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था स्थापित हुई। पाश्चात्य देशों और विशेषकर यूरोप में यह व्यवस्था 18वीं और 19वीं शताब्दियों में प्रचलित रही। काप्लान के अनुसार इस व्यवस्था में काम करने वाले राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राज्य होते हैं जो एक उप-श्रेणी के रूप में राष्ट्रीय राज्य भी होते हैं। शक्ति-सन्तुलन-व्यवस्था का अनुभव बतलाता है कि इस व्यवस्था में कम से कम 5 अथवा 6 मुख्य राष्ट्रों का होना आवश्यक है। प्रथम महायुद्ध से पूर्व इंग्लैंड, फ्राँस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य, इटली तथा संयुक्तराज्य अमेरिका प्रधान राष्ट्रीय राज्य थे। काप्लान के अनुसार शक्ति-सन्तुलन की इस व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए छ महत्वपूर्ण नियमों का पालन किया जाना जरूरी है—(1) प्रत्येक मुख्य राष्ट्र (Essential Actor) राजनय के माध्यम से अपनी क्षमताओं में वृद्धि करे, युद्ध के माध्यम से नहीं; (2) प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य का प्रमुख कर्तव्य अपने हितों की सुरक्षा है और क्षमताओं के विकास के दिना हितों की सुरक्षा सम्भव नहीं है, अतः यदि आवश्यक

हो तो युद्ध का गहरा उठावर भी अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए; (3) युद्ध की व्यवस्था में मुख्य सन्तुलाय का गंभीरता करने की अपेक्षा युद्ध रोका जाए; (4) राष्ट्रों के बिगो भी ऐसे गुट के निर्माण का विरोध करना जो व्यवस्था में प्रमुख अथवा प्राथमिक की स्थिति ग्रहण करें; (5) बिगो भी शक्ति अथवा राष्ट्र की अथवा अन्य राज्यों की राष्ट्रोंपर मिडानों पर घटने में रोचना; एवं (6) बिगो भी मुख्य पराजित राष्ट्रों की व्यवस्था में पुनः शामिल कर लेना। मार्टिन बाप्पान का विश्वास है कि इन नियमों का पालन न होने पर शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था भंग होने की सम्भावना रहती है। 18वीं और 19वीं शताब्दियों में इस व्यवस्था ने एक पूर्ण व्यवस्था के रूप में कार्य किया और इसे एक नियम के रूप में व्यापक मान्यता मिली। लेकिन बाद में उपर्युक्त नियमों का समुचित पालन न होने से यह व्यवस्था भंग हो गई और परिणामस्वरूप हमें महायुद्ध का सामना करना पड़ा। बाप्पान के अनुसार शक्ति-सन्तुलन के भंग होने पर विभिन्न शक्तियों में जो भारी असन्तुलन पैदा हो जाता है, उसके फलस्वरूप इस व्यवस्था का रूपान्तरण भी हो जाता है।

बाप्पान के अनुसार शक्ति-सन्तुलन-व्यवस्था का सर्वाधिक सम्भावित रूपान्तरण द्विध्रुवीय व्यवस्था में होता है। यह परिवर्तन तब होता है जब दो राष्ट्रीय राज्य अपने महत्वपूर्ण राज्यों के साथ दो भिन्न-भिन्न गुटों पर नेतृत्व स्थापित कर लेते हैं। बाप्पान ने इस द्विध्रुवीय व्यवस्था के दो रूप बनाए हैं—निधित्व द्विध्रुवीय व्यवस्था और बटोर अथवा दुर्ग द्विध्रुवीय व्यवस्था। जैसा कि पहले चर्चा किया जा चुका है, निधित्व स्वरूप में शक्ति-गुट के अन्तर्गत मनभेद की गुंजाइश रहती है—साम तौर पर तटस्थ राज्यों के अस्तित्व की वजह से जबकि दुर्ग व्यवस्था में ऐसी गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि तटस्थ राज्य इस व्यवस्था से सम्बद्ध नहीं होते।

बाप्पान के मन में मार्शभास अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास तब सम्भव होता है जब निधित्व द्विध्रुवीय व्यवस्था के मुख्य राज्यों (Essential Actors) के कार्यों का विस्तार हो जाता है। इस व्यवस्था में मार्शभास अथवा विश्वव्यापी संगठन (A Universal Actor, जैसे कि समुक्त राष्ट्रमण) राष्ट्रीय राज्यों (राष्ट्रों) के मध्य युद्ध रोकने की दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन राष्ट्रीय राज्य अर्थात् विभिन्न राष्ट्र अपना अस्तित्व कायम रखते हैं और राष्ट्रीय हितों तथा अधिनाधिक शक्ति-अवयव के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। बाप्पान के विचारानुसार यह सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक एकीकृत व्यवस्था (An Integrated System) होगी जो न्यायिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि सभी कार्य करेगी। राष्ट्र इस एकीकृत व्यवस्था के ढाँचे में (जैसे विश्वमंडल) रहते हुए ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सम्पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी अर्थात् राष्ट्रीय हित इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हितों के अधीनस्थ समझे जाएंगे और सभी राष्ट्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों का प्रयास करेंगे, यहाँ तक कि बल-प्रयोग की धमकी भी नहीं देंगे। राष्ट्रीय राज्य अपनी नीतियाँ असाध्यवश ऐसी बनाएँगी जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व को बल

मिले। पर चूँकि इस प्रकार की सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी, अतः इस बात की पूरी सम्भावना है कि समुचित रूप में स्थापित ग्रहण करने पर्याप्त काफ़ी लम्बे समय तक इस व्यवस्था में प्रस्थिरता प्राप्त रहेगी।

यदि उपर्युक्त व्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो गई तो सम्भव है कि वह श्रेणीबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रूप ग्रहण करले जिसमें सभी राष्ट्र व्यावहारिक रूप से एक शक्तिशाली राष्ट्र के नेतृत्व में आ जाएँगे। काप्लान के अनुसार यह व्यवस्था निदेशात्मक (Directive) भी हो सकती है और अ-निदेशात्मक (Non-directive) भी। निदेशात्मक श्रेणीबद्ध व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब नाज़ी व्यवस्था के समान कोई एक राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था (A National Actor System) विध्व-विजय करले। अ-निदेशात्मक व्यवस्था तब होगी जब वह उन राजनीतिक नियमों पर आधारित हो जो सामान्यतः तोरनन्त्रों में प्रचलित होते हैं। काप्लान का मत है कि एक निदेशात्मक श्रेणीबद्ध व्यवस्था में समूहों और व्यक्तियों के बीच तनाव बहुत अधिक रहने की सम्भावना होती है जबकि अ-निदेशात्मक श्रेणीबद्ध व्यवस्था में तनाव अपेक्षाकृत बहुत कम होता है।

काप्लान की योजना में छठी और अन्तिम अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था है जिसमें इस प्रकार के घातक असुरों का अस्तित्व होगा कि कोई भी राष्ट्र स्वयं नष्ट होने में पहले दूसरों को नष्ट कर देने में समर्थ हो। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें प्रत्येक राज्य के पास मान्य निषेधाधिकार होगा अर्थात् उसके खुद के निर्णय ही अन्तिम होंगे। इस प्रकार यह विभिन्न व्यवस्था हाथ में धरिणित प्रकृति की व्यवस्था होगी जिसमें सभी हितों में परस्पर विरोध होता है और सभी एक दूसरे के विरुद्ध युद्धरत होते हैं। इस व्यवस्था की मुख्य बात यही है कि प्रत्येक राज्य दूसरे को नष्ट कर देने की दृष्टि से समान रूप से समर्थ होगा। स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में राष्ट्र केवल एक ही स्तर पर (Only at One Level) काम रह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था में सार्वभौमिक सगठनों का अस्तित्व नहीं हो सकता। काप्लान के मतानुसार यह इकाई-निषेधाधिकार-व्यवस्था शेष पाँचों व्यवस्थाओं (शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था, द्विद्वितीय व्यवस्था आदि) में से किसी से भी विकसित हो सकती है पर यह श्रेणीबद्ध व्यवस्था से तब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक कि वह व्यवस्था आन्तरिक शीघ्रता की प्रक्रिया में न हो। इस बात की सम्भावना भी बहुत कम है कि यह सार्वभौमिक व्यवस्था से विकसित हो सके। काप्लान की दृष्टि में इकाई-निषेधाधिकार व्यवस्था स्थायी तभी सिद्ध हो सकती है जब गड़बड़ या शान्ति भंग करने वाले राष्ट्र के विरोध में शेष सभी राष्ट्र सामूहिक रूप से खड़े हो जाएँ। यदि कोई भी राष्ट्र असहिष्णु और दुर्घर्ष (Unresistant) है तो व्यवस्था समाप्त होने लगेगी अथवा कम से कम सामयिक रूपान्तरण की ओर प्रवृत्त हो जाएगी।

(5) नीति-विज्ञान सम्बन्धी दृष्टिकोण

(Policy-Science Approach)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में प्रयत्न करते हुए

अमेरिकी विद्वानों ने अन्य समाजशास्त्रों और विभिन्न विधियों का महारा लेने हुए इस क्षेत्र में नीति-विज्ञान सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस पद्धति में उन परिस्थितियों का व्यापक विवेचन किया जाता है जिनके अन्तर्गत विदेश-नीतियों का निर्धारण होता है। देश के निवासी, उनका चरित्र, उनकी भाषाएँ-भाषाशास्त्र, नेतृत्व, सामाजिक एवं प्रजागरीय दशा, आदि उन विभिन्न बातों को परिस्थिति में सम्मिलित किया जाता है जो नीति-निर्धारण-प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इस नीति-विज्ञान-मार्ग दृष्टिकोण के अन्तर्गत अनेक दृष्टिकोण अथवा पद्धतियाँ विकसित हुई हैं जैसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण (Behavioural Approach), गेन-मिथान (Game Theory), मोदेबाजी का मिथान (Bargaining Theory), आदि। आज राजनीति विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अमेरिकी दृष्टिकोण प्रमुखा प्राप्त कर रहे हैं और विलक्षणता भी लिए हुए हैं। उनके गेन-मिथान, मोदेबाजी का मिथान आदि का आगे कुछ विस्तार से उल्लेख किया जाएगा और 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सामान्य मिथान' (A General Theory of International Politics) के बहुचर्चित पक्ष पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

क्षेत्र-सिद्धान्त (Field Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में एक धारणा विश्व को एक अप्रतिबद्ध क्षेत्र के रूप में (World as an Uncommitted Field) देखने की है। यह विचार विश्व को अलग-अलग क्षेत्रों (Fields) से युक्त मानता है और इसी आधार पर स्विगी राइट ने पृथक् से क्षेत्र-मिथान्त (Field-Theory) का प्रतिपादन किया है। क्षेत्र-मिथान्त के अनुसार यह विश्व विविधतापूर्ण और अत्यन्त जटिल (Complicated) है। एक क्षेत्र के निवासियों की मूल्य-व्यवस्था (Value System), सामाजिक संस्थाएँ (Social Institutions) तथा सरकार के रूप (Forms of Govt.) उनके अपने होते हैं जो दूसरे क्षेत्र में नहीं अपनाए जा सकते। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली विविधताओं को दूर करना न तो सम्भव है और न आवश्यक ही।

नीतियों को बनाने, निष्णों को लेने तथा उनको व्यावहारिक रूप देने का काम किसी एक का नहीं होता। इस कार्य में राज्य, सरकार, राष्ट्र और जनता सभी का सहयोग रहता है। आवश्यक नहीं कि एक क्षेत्र की जनता का स्तर वही हो जो वहाँ सरकार का है। सरकार के अपने कुछ ऐसे मूल्य हो सकते हैं जो जनता के मूल्यों से भिन्न हो तथा जो उस देश की संस्कृति तथा राज्य के कानूनों में समाहित मूल्यों का प्रतिनिधित्व न करते हो। इन दोनों मूल्यों के बीच मध्य होता है—देश में स्पष्टतः दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष में सरकार एवं प्रशासक रहते हैं और दूसरे पक्ष में जनता अथवा प्रशासित रहते हैं। यदि शासन-व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक है तो जनता का पक्ष विजयी होगा और यदि तानाशाही है तो शासक या सरकार की मनमानी चलेगी अर्थात् जिसके हाथ में शक्ति है वह दूसरे के मूल्यों को कुचल देगा। क्षेत्र-सिद्धान्त वालों का दावा है कि उनका सिद्धान्त इस दृष्टि से पृथक् है

और दूसरे सिद्धान्त यह मानकर चलते हैं कि एक दिन सभी लोग एक प्रकार की विश्व-व्यवस्था (World Order) पर एकमत हो जाएंगे। क्षेत्र-सिद्धान्त यह मानता है कि 'क्षेत्र' (Field) है, सम्भवतः भविष्य में कभी मतों (Opinions) में एकता की थोड़ी बहुत स्थापना कर सके, किन्तु अभी तो जैसे इसके कार्यों की व्यवस्था में तथा उनके प्राप्त की सम्बन्धों में परिवर्तन होता है, इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। एक क्षेत्र के निवासियों के मूल्य, भावनाएँ एवं लक्ष्य आदि जब तक एक जैसे रहते हैं तब तक तो उनके मतों में भी सामञ्जस्य रह सकता है, किन्तु ज्यों ही उनके पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन आता है त्यों ही उनके बीच मतभेद भी हो जाता है। हो सकता है कि 'क्षेत्र' भविष्य में एक सभायोजित वैधानिक व्यवस्था व एक स्थायी संतुलन या एक समर्थ संगठन बन जाए, या कोई गद्गभावपूर्ण समुदाय बन जाए, किन्तु सिद्धान्त इनमें से किसी को अपना लक्ष्य बना कर नहीं चलता। इस विचारधारा का उद्देश्य यह नहीं है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का दर्शन या उनके व्यवहार की कला का घादश (Model) प्रस्तुत करे वरन् यह तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास की व्याख्या करने अथवा उसे वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास करती है।¹

विन्नी राइट का कहना है कि क्षेत्र-सिद्धान्त को सामान्य सिद्धान्त माना जा सकता है। साम्राज्यवादी युग में जिस विचारधारा का प्रभाव था, यह विश्व को एक योजना मान कर चलती थी। राष्ट्रीयतावाद के युग में यह विचारधारा महत्वहीन हो गई तथा इसका स्थान शक्ति-संतुलन को महत्व देने वाली विचारधारा ने ले लिया। अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के वर्तमान युग में शक्ति-संतुलन के विचार भी असम्भविक बन गए हैं और आज विश्व-संगठन एवं विश्व-सरकार की मान्यता को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रो. विन्नी राइट का विचार है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्र-सिद्धान्त को अपना लिया गया तो यह कभी भी असम्भविक न बनेगा क्योंकि यह परिवर्तन का विरोध नहीं करता वरन् उसको मान कर चलता है तथा अनुकूल समायोजित होने का प्रयास करता है।

खेल तथा सीदेबाजी का सिद्धान्त (Games and Bargaining Theory)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा इसकी व्याख्या जिन तीन विद्वानों ने की है उनके नाम हैं—काप्लान (Morton A. Kaplan), बर्न्स (Arthur Lee Burns) तथा क्वॉट (Richard E. Quandt)। इन विद्वानों ने खेल-सिद्धान्त के आधार पर शक्ति-संतुलन (Balance of Power) की सिद्धान्तिक व्याख्या की है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए खेलों का माध्यम अपनाया है। इस प्रणाली में अधिक समय तथा शक्ति की आवश्यकता होती है, नहीं तो अथ तब इसका काफी विकास हो गया होता।

1 Quincy Wright : "Development of a General Theory of International Relations", in the role of theory in International Relations, edited by Harrison, p. 40.

यह मिडान्ग उन मोर्चों के लिए बहुत उपयोगी है जो एक विशेष समस्या पर निर्णय लेना चाहते हैं, जो एक बौद्धिक मिडान्ग चाहते हैं, अथवा जो अपने विचारों को तुलनात्मक रूप में उपयोगिता देना चाहते हैं। बुद्ध-नीति के बारे में गेन मिडान्ग बहुत-बुद्ध कहता है तथा एक व्यक्तिपरक रूप में कहता है। जहाँ यह मिडान्ग लागू हो जाता है, वहाँ झूठे रहने की सम्भावना काफी कम हो जाती है। गेन-मिडान्ग को यदि अच्छी प्रकार समझ लिया जाए तो हम उन समस्याओं को भी जान सकते हैं जिन पर अभी गेन-मिडान्ग को लागू नहीं किया गया है।

एक गेन की भाँति हम मिडान्ग में भी स्वयं के नियम (Rules), खिलाड़ी (Players), विचारों (Moves), रणनीति (Strategies), तथा छतिपूर्ति (Pay off) धारि होते हैं। यह गेन स्पर्धापूर्ण (Competitive) तथा सहकारितापूर्ण (Co-operative) दोनों ही प्रकार का हो सकता है। गेन के सैद्धान्तिक विस्तारों की इकाई खिलाड़ी होता है। यह अभिनेता (Actor) होता है। अन्तर्राष्ट्रीय गेन में खिलाड़ी दो भी हो सकते हैं तथा अधिक भी। खिलाड़ी का सर्व उद्देश्य है जो निर्णय लेता है। खिलाड़ी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए या प्रतिद्वन्द्वी की शक्ति को कम करने के लिए जिनमें सन्धिही करता है वे राष्ट्र खिलाड़ी नहीं माने जाते।

गेन के नियम होते हैं। इन नियमों पर खिलाड़ियों का बल नहीं रहता। जैसे शतरंज का नियम है कि पैदल मोहरा एक बार में एक या दो घर पार कर सकता है, इसी तरह अमेरिकी शासन-व्यवस्था में नियम है कि जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त हो जाए वही राष्ट्रपति बन जाता है। गेन-मिडान्ग उन नस्लों को ध्यान में नहीं रखता जो अन्तर्राष्ट्रीय गेन पर प्रभावी नहीं होते। गेन के नियम ही यह निर्णय करने हैं कि एक खिलाड़ी क्या कदम उठाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सामाजिक नियम स्पष्ट होने की अपेक्षा सचीने होते हैं, जैसे कि 'शक्ति-सन्तुलन' के अनुसार यह धारणा की जाती थी कि एक राष्ट्र उस पक्ष में नहीं मिलेगा जो पहले से ही शक्तिशाली है; किन्तु यह भी सम्भव है कि वह देश उस पक्ष में मिल जाए।

सामान्य गेमों की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का खेल भी दो प्रकार का होता है—(1) जिसमें कि सभी विचारों तथा उनके परिणामों की सूचना खिलाड़ी को दे दी जाए, (2) जिसमें हम प्रकार की सूचना न दी जाए। सूचना पूर्ण तथा अधूर्ण दोनों ही प्रकार की हो सकती है। हम गेन में खिलाड़ी के सामने कुछ विचारों में से चुनाव करने की स्वतन्त्रता भी रहती है। एक बार डॉ. राधाकृष्णन् ने कहा था कि ताग के खेल में हमारे पास क्या पत्ते आएँगे, यह हमारे अधिकार की बात नहीं है किन्तु जो पत्ते आए हैं उनका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे यह बहुत कुछ हमारी स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति पर आधारित है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ व स्थितियाँ किस करवट बैठती हैं, यह एक राष्ट्र की शक्ति के बाहर की बात है; किन्तु उन स्थितियों में वह किस विचारों को चुनेगा यह उसी की इच्छा पर निर्भर है। एक विचार के चुनने का परिणाम क्या होगा यह भी बहुत कुछ अनिश्चित हो होता है,

क्योंकि 'परिणाम' पर दूसरे राष्ट्र द्वारा चुने गए विकल्पों का भी प्रभाव पड़ता है जो अनिश्चित है।¹ खेल भी कई प्रकार के होते हैं जैसे—

1. **Zero-sum Games**—जिसमें कुछ सिलारियों की हानियों (Losses) का भ्रम दूसरे सिलारियों का लाभ (Gains) होता है।

2. **Constant-sum Games**—इस खेल को समझने के लिए हम एक बाजार की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कुछ सामान एक निश्चित मर्याद व कीमत में बिकते हैं। इस बाजार के प्रतिद्वन्द्वी जो लाभ प्राप्त करेंगे वह दूसरे की हानि देकर नहीं करेंगे। सभी को समान लाभ मिलेगा।

3. **Non-Zero-sum Games**—यह खेल उक्त दोनों के बीच का है। हममें प्रतिद्वन्द्वियों के बीच का सम्बन्ध सहयोगितापूर्ण भी रह सकता है और परस्पर विरोधी भी।

शक्ति के खेल का एक उदाहरण

(An Example of the Game of Power)

शक्ति का खेल विभिन्न राष्ट्रों द्वारा खेला जाता है। ये राष्ट्र एक मेज के चारों ओर बैठ जाते हैं और गोठियों के माध्यम से प्रतियोगिता करने लगते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के पास एक बोर्ड होता है। इस बोर्ड पर वे सीमाएँ अंकित रहती हैं जिनका वह प्रत्येक अन्य प्रतियोगी के साथ हिस्सेदार है। साथ ही उसका स्वयं का प्रदेश भी अंकित रहता है। गोठियाँ खोतों की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिस देश के पास जिनकी अधिक गोठियाँ हैं वह उतने ही अधिक खोतों का स्वामी माना जाएगा। कुछ गोठियाँ सुरक्षित सेनाओं (Reserved Forces) के रूप में भी रखी जा सकती हैं। जब इनको दूसरे देशों के विरुद्ध सीमा पर लगा दिया जाता है तो वे विध्वंसक शक्ति का भ्रम बन जाती हैं। जिन खोतों को प्रयुक्त नहीं किया जाता अर्थात् जिनको न तो सीमाओं पर ही लगाया जाता है और न ही सुरक्षित सेना के रूप में रखा जाता है, वे आनुपातिक मात्रा में आय कमाती हैं, किन्तु यह अनुपात प्रत्येक बार अवसर के अनुसार बदलता रहता है।

चलने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी की अपनी बारी आती है। यदि कोई चाहे तो वह अपनी बारी को छोड़ भी सकता है अथवा इसे स्वीकार कर अपनी शक्तियों को कार्यरत कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है या वापस ले सकता है अथवा जो सेनाएँ पहले से ही सीमा पर भेजी जा चुकी हैं उनके द्वारा युद्ध प्रारम्भ कर सकता है। यदि युद्ध प्रारम्भ हो जाता है तो उस सीमा पर की गोठियाँ विरोधी पक्ष की गोठियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगी। प्रत्येक पक्ष उस समय तक गोठियों की सीमा पर भेजता रहेगा जब तक कि दूसरे पक्ष की सारी गोठियाँ समाप्त नहीं हो जानी। चलने की नियमित बारी को उस समय तक के लिए रोक दिया जाता है जब तक वह संघर्ष अथवा युद्ध समाप्त नहीं हो जाता अथवा जब तक कि कोई पक्ष के पास

पुनः सेना भेजने तथा युद्ध को प्रारम्भ करने का अवसर होता है। दूग सेन के गिलाड़ियों को यह निर्दिष्ट रहता है कि यह सेना या तो समाप्त होने तक सेना जाएगा यथवा कुछ विशेष कारियों के बाद समाप्त हो जाएगा। कारियों की संख्या गोठियों की संख्या पर निर्भर करती है।

गन्धि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में हो जानी है और जब गन्धि हो जाती है तो सम्बन्धित देश सम्मान्य शीमाओं पर से अपनी सेनाओं को हटा लेते हैं। जब एक देश दूसरे देश के विरुद्ध शीमा पर अपनी सेना को बढ़ाता है तो वह दबाव हातने की स्थिति में हो जाता है। त्रिग देश का दबाव जितना अधिक होता है, शीमा पर उगकी प्रभुता उतनी ही अधिक मानी जाती है।

शक्ति के दूग सेन का उद्देश्य यह होता है कि सेन के अन्त तक यथासम्भव अधिक गोठियाँ प्राप्त करनी जाएँ। यदि सेन की समाप्ति के बाद एक गिलाड़ी के पास चोरी-ची गोठियाँ ही बच जाती हैं तो वह हारा हुआ गिलाड़ी माना जाता है। सेन से पूर्व ही गिलाड़ियों द्वारा जो समस्या तय कर दी गई थी, यदि किसी गिलाड़ी के पास उग समस्या में कम गोठियाँ बच पानी हैं तो उगको शून्य प्रदान किया जाता है तथा उगकी गोठियों को उन सभी गिलाड़ियों में बाँट दिया जाता है जिनके पास कम से कम दूनी गोठियाँ हो जिनकी के साथ उन्होंने सेना प्रारम्भ किया है।

गिलाड़ियों द्वारा सेन प्रारम्भ करने से पूर्व ही यह तय कर लिया जाता है कि जितनी कारियों के बाद सेन को समाप्त कर दिया जाएगा। जब दो से अधिक गिलाड़ी सेनते हैं और अपनी गोठियों में अधिक समस्या तक की कारियों तक सेनते हैं तो वह सेन समाप्ति उत्तेजक बन जाता है। गिलाड़ियों की समस्या जितनी कम होती है उनकी बारी घाने में उतना ही कम समय लगता है।

सेन के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में एक बड़े छात्रा की मेज होनी चाहिए त्रिग पर 20×30 इंच के दो नक्शे रगे जा सकें तथा उनके बीच कोई ऐसा प्रतिरोध लगाया जा सके कि गिलाड़ी एक दूसरे के नक्शों को तथा एक दूसरे के चेहरों को न देख सकें। उनका एक मानीटर होना है जो एक ही समय में दोनों नक्शों पर नजर रखता है। गिलाड़ी वैकल्पिक रूप से कमरे के दोनों ओर बैठाए जाते हैं। उनको टेलीफोन पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर दिया जाता है। जहाँ सेल व्यक्तिओं की जगह टीम के बीच होता है वहाँ गोपनीयता की दृष्टि से दो कमरों की आवश्यकता होती है। यह सेल जिस रूप में खेला जाना है उसमें केवल कुछ घण्टे ही लगते हैं। गिलाड़ी को सेल की तकनीक समझाने में ही लगभग एक घण्टा व्यतीत हो जाता है। प्रत्येक गिलाड़ी को यह समझा दिया जाता है कि वह सापेक्षिक रूप से अधिक नम्बर पाने के लिए नहीं बरन् सम्पूर्ण नम्बरों को पाने के लिए खेल रहा है। कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो सेल में बिम्बप्रता ला सकती हैं। उदाहरण के लिए, राज्यों के मूल्य अलग-अलग हो सकते हैं, दो गिलाड़ियों की मूल्य-व्यवस्था का पारस्परिक सम्बन्ध अलग-अलग हो सकता है। प्रत्येक गिलाड़ी को अपने प्रतिपक्षी के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त है उसकी मात्रा भी अलग-अलग हो

सकती है। संचार-व्यवस्था का रूप भ्रम-भ्रम हो सकता है। संचार-व्यवस्था सीधी हो सकती है यह प्रत्येक प्रकार की बात के लिए स्वतन्त्र हो सकती है अथवा केवल कुछ प्रस्तावों एवं कथनों तक ही सीमित हो सकती है। इस प्रकार शक्ति के खेलों के बीच अनेक विभिन्नताएँ पाई जा सकती हैं।

ये खेल प्रायः उन सौदेबाजियों के प्रायोगिक अध्ययन होते हैं जो सीमित युद्ध अथवा अन्य संधियों में की जाती हैं। यह सौदेबाजी शब्दों के आधार पर भी की जाती है और कार्यों के आधार पर भी। इन सौदेबाजी में संचार-व्यवस्था को कमजोर रखा जाता है, इसे कानूनी रूप में लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। जब सौदेबाजी करने वाले भागीदार एक-दूसरे से सम्पर्क करते हैं तो वे एक-दूसरे के मूल्यों से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं। वैसे उनके पास एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए पर्याप्त शक्ति रहती है। सौदेबाजी की इस स्थिति को खेल का रूप देकर उस पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान एवं खोजें की जाती हैं।

वर्तमान समय में प्रयोग के लिए जिन खेलों को अपनाया जाता है वे युद्ध के सदृश नहीं होते। अनुसंधान हेतु आयोजित इन खेलों तथा परम्परागत युद्ध के खेलों के बीच अन्तर होता है। प्रथम अन्तर तो यह है कि प्रायः सभी युद्ध-खेल पूर्ण रूप से जीरो-सम (Zero-sum) खेल होते हैं। इनमें विरोधियों के साथ सहयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। विजेता केवल वही माना जाता है जो अपने प्रतिद्वन्दी को समाप्त कर सके अथवा उसको दबा सके। दूसरे, इस खेल को जो रूप दिया जाता है वह युद्ध जैसा नहीं होता। इसमें कम से कम तकनीकी जटिलता रहती है। इसे प्रतिक्षण की अपेक्षा शोध-कार्य के लिए व्यवस्थित किया जाता है। इसका रूप अत्यन्त सरल बनाया जाता है। इसमें सैद्धान्तिक दृष्टि से मापन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि किया जा सकता है। कई बार खेलों का आयोजन सुविधाजनक बनाने के लिए इनको कम खर्चीला बनाया जाता है। इसमें अधिक प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं होती।

खेल सिद्धान्त की प्रक्रिया

(The Methodology of Game Theory)

प्रायोगिक खेल-सिद्धान्त के द्वारा सौदेबाजी की प्रक्रिया का व्यावहारिक अध्ययन किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि कोई भी औपचारिक सिद्धान्त या विचारधारा अपने आप में अपर्याप्त होती है। कम से कम सौदेबाजी के खेलों में यह आवश्यक रूप से अपर्याप्त होती है। इस प्रकार के खेलों में एक अनिश्चितता की मात्रा रहती है। खेल की मात्रात्मक बनावट द्वारा जो दावाएँ प्रस्तुत की जाती हैं वे किसी भी सुझाव का निर्णय करने के लिए उसे अपर्याप्त बना देती हैं, यहाँ तक कि बुद्धिपूर्ण एवं धार्मिक रूप से समायोजनपूर्ण खेल में भाग लेने वालों के व्यवहार की रणनीतियाँ भी कुछ उपयोगी नहीं बनती। इस प्रकार के किसी भी खेल में वस्तु-स्थिति को समझने के लिए अभिप्रायों की जानने एवं उनका अनुमान लगाने के लिए, प्रत्येक की समायोजित आकांक्षाओं तक पहुँचने के लिए और एक सीमित युद्ध में सीमा

निर्धारित करने के लिए आवश्यक भाग्यता, परम्परा एवं रोक बिकसित करने के लिए कार्यों में एकीकरण की आवश्यकता होती है। एक खेल में भाग लेने वाले लोग एक दूसरे की आकांक्षाओं का ज्ञान कराने के लिए किस प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रिया करेंगे, वे अपने अभिप्रायों को जताने के लिए कौन से साधन अपनाएँगे तथा वे समुक्त रूप से किन नियमों एवं परम्पराओं को जानेंगे मानेंगे—ये सारी बातें पहले से ही तय नहीं की जा सकती। चाहे कोई खिलाड़ी कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो इनके बारे में पहले से ही कुछ तय नहीं कर सकता। खेल-सिद्धान्त में व्यावहारिक अध्ययन का आवश्यक तत्व रहता है। बौद्धिक व्यवहार की विचारधारा द्वारा जो तरीका सुझाया जाता है एक खेल के खिलाड़ी उससे भिन्न रूप में भी व्यवहार कर सकते हैं। यह भिन्नता बुराई की अपेक्षा अच्छाई की दिशा में भी अप्रसर हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में खिलाड़ी उससे भी अच्छा व्यवहार कर सकते हैं जैसा कि एक शुद्ध औपचारिक बौद्धिक व्यवहार की विचारधारा द्वारा सुझाया जाता है। ये खिलाड़ी अच्छा व्यवहार किस तरह कर सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सैद्धान्तिक विश्लेषण किया जा सकता है, किन्तु अन्त में उसे व्यवहार के आधार पर ही प्रमाणित करना होता है। खेल-सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह किया जाता है कि इसके आधार पर हम जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं अथवा जिस वातावरण को देखते हैं क्या उसके आधार पर वास्तविक संघर्ष की स्थितियों का अथवा वास्तविक सौदेबाजी की प्रक्रियाओं का सामान्यीकरण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि इस प्रकार का खेल वास्तविक संघर्ष की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को सामने नहीं लाता। यह हमारे सामने कोई ऐसा सन्तुलित प्रतिमान नहीं रखता जिसमें सभी तत्वों को पर्याप्त महत्त्व प्राप्त हो। इसका मुख्य उद्देश्य समस्या के उन पहलुओं को सामने लाना है जो विश्लेषण के लिए सन्देह प्रदर्शित करने हैं अथवा प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोगों को सन्देह की नजर से देखते हैं। इस प्रकार के खेल द्वारा खिलाड़ियों की ज्ञान एवं सूचना सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला जाता है, उनके भावनात्मक व्यवहार या व्यक्तिगत मूल्य-व्यवस्था पर नहीं। जहाँ तक सम्भव होता है वहाँ तक खिलाड़ी की मूल्य-व्यवस्था उसे खेल द्वारा ही प्रदान की जाती है। यदि रोकने पर भी भावनात्मक पक्ष उभर आता है तो उसका स्तर उस मनमुटाब, जलन, ईर्ष्या आदि से भिन्न होता है जो वास्तविक संघर्ष एवं जीते-जागते युद्ध की स्थिति में हो सकता है। इस प्रकार के खेल में व्यक्तियों के व्यवहारों एवं संगठनात्मक व्यवहार, नौकरशाही के व्यवहार, सामूहिक राजनीतिक व्यवहार एवं अन्य समुक्त निर्णय प्रक्रियाओं पर भाग लेने वाले व्यक्तियों की विशेषताओं एवं सामर्थ्य के द्वारा सीमाएँ लगाई जाती हैं।

इस प्रकार के खेल की इतनी अधिक सीमाएँ होती हैं, किन्तु फिर भी यह सीमित युद्ध तथा ऐसे संघर्षों के कुछ तत्वों को जानने के लिए एक आकर्षक साधन प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास अनुभवात्मक रूप में वस्तु-स्थिति का अध्ययन करने के लिए बहुत कम विकल्प हैं। खेल के आधार पर किए

जाने व.ले प्रयोगों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होना है वह यद्यपि पर्याप्त व्यापक या विश्वसनीय नहीं होता, तथापि दूसरे तरीकों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की तुलना में यह अचूक प्रतीत होता है। खेल-सिद्धान्त से प्राप्त निष्कर्षों या परिणामों का एक अन्य महत्व यह है कि यथार्थ जगत् में भी ये कुछ उपयोगी सिद्ध होने हैं। सीमित युद्ध, औद्योगिक संघर्ष आदि के बारे में अनेक प्रस्ताव सामान्य रूप में रखे जाते हैं तथा उन्हें इतने सरल एवं सामान्य प्रमाणों या तर्कों पर आधारित किया जाता है कि वे उतनी सरल और बनावटी स्थिति पर लागू किए जा सकें जो खेल द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि यद्यपि खेल के निष्कर्षों की उपयोगिता एवं प्रामाणिकता सदिग्ध है, फिर भी किसी अन्य सिद्धान्त द्वारा इनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रायोगिक खेलों की उपयोगिता को इस आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है कि हम सामान्य रूप से तर्क करने पर जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं उनको खेल प्रक्रिया द्वारा असत्य सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम खेल का अध्ययन करते हैं। इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का मूल्य-व्यवस्था के प्रति अनभिज्ञ है अथवा उसे यह जानकारी नहीं है कि दूसरे खिलाड़ी को चलने के कितने अवसर प्राप्त होंगे अथवा वह कितनी बार चल सकता है। ऐसी स्थिति में यदि हम यह प्रस्ताव करें कि प्रत्येक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी की मूल्य-व्यवस्था का, उनकी चाल के अवसरों का तथा जितनी बार वह चल चुका है इसका ज्ञान करा दिया जाए तो दो खिलाड़ियों को इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? इस प्रश्न के सम्बन्ध में यदि बौद्धिक रूप से विचार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि जिस खिलाड़ी को अपने विरोधी के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त है, वह लाभ में रहेगा; किन्तु जब हम इस बात को तर्कों के आधार पर नहीं, बल्कि खेल के आधार पर जानने की चेष्टा करते हैं तो विदित होता है कि इसमें दोनों ही खिलाड़ियों को लाभ हो सकता है अथवा दोनों को हानि हो सकती है। यह वह खेल नान-जीरो-सम (Non-Zero-sum) प्रकार का है तो प्रस्ताव को दूसरे रूप में रखा जा सकता है कि अन्य चीजें समान होने पर उन खिलाड़ियों को अधिक प्राप्ति मिलेगी अथवा अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा जिसे अपने विरोधी के सम्बन्ध में अधिक सूचनाएँ प्राप्त हैं। यह प्रस्ताव एक दोषपूर्ण तर्क प्रक्रिया पर आधारित है, किन्तु यह बुद्धि-मंगल प्रतीत होता है। यदि हम इसकी गलती को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसके लिए खेल का तरीका अपनाना होगा। जो लोग इस प्रकार के प्रस्ताव को मानते हैं उनकी मान्यता का आधार सामान्य सूझ-बूझ होनी है। यह सूझ-बूझ इतनी सामान्य होती है कि यदि खेल द्वारा प्रस्ताव को दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया गया तो इसमें विरोधाभास पैदा हो जाएगा।

इस उदाहरण से खेल की प्रक्रिया का एक अन्य पहलू प्रकट होता है। खेल का प्रयोग सरल होता है कि उसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके। जब इस खेल के परिणाम आशा के विपरीत होने हैं तो इनके कारणों का आसानी से समझा जा सकता है। प्रयोगात्मक खेल द्वारा जिस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है

उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि हर बार खेले जाने वाले खेलों द्वारा उसका समर्थन किया जाए। जब एक बार प्रयोगात्मक खेल द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच गए तो उस निष्कर्ष का सैद्धान्तिक रूप में बौद्धिकीकरण कर देना चाहिए। इस प्रकार प्रयोगात्मक खेल सैद्धान्तिक मॉडल का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है। इस मॉडल के सक्रिय भागों को उस समय अच्छी तरह समझा जाता है जबकि उनको प्रायोगिक रूप प्रदान किया जाए।

इसी बात को अन्य रूप से भी स्पष्ट किया जा सकता है। प्रयोगात्मक खेलों का प्रयोग उन महत्वपूर्ण सम्भावनाओं को खोजने एवं प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है जो अन्य प्रकार से प्रकट नहीं होती। इन सम्भावनाओं का महत्व एवं उपयोगिता तार्किक रूप से अथवा अन्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध की जा सकती है, किन्तु इन सम्भावनाओं का अस्तित्व है तथा ये सम्भावनाएँ अन्य भागों से किस प्रकार सम्बन्धित हैं, यह बात केवल प्रयोगात्मक खेल द्वारा ही खोजी जा सकती है। उदाहरण के लिए एक सम्भावना यह है कि अधिक ज्ञान और सूचना रखने वाले खिलाड़ी को लाभ प्राप्त न हो और अन्य खिलाड़ी को प्राप्त हो जाए जिसे इतनी सूचना और ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि नई सूचना प्राप्त करने पर यदि वह उस सूचना को गुप्त न रख सके तो एक खिलाड़ी को लाभ होने की अपेक्षा नुकसान हो सकता है।

कुल मिलाकर यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्ष सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित नहीं होंगे। हमारा अभिप्राय यह रहता है कि परीक्षण किए गए वातावरण को किसी सिद्धान्त से सम्बन्धित करें तथा साथ ही निरीक्षण किए जाने वाले तत्त्वों के सम्भावित महत्व को प्रदर्शित करें। प्रयोगात्मक खेल में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि खेल की बनावट सम्बन्धी विशेषताओं को किस प्रकार रखा जाए कि उनके द्वारा कुछ विशेष परिणाम एवं वातावरण प्राप्त किए जा सकें। इस प्रकार प्रयोगात्मक खेल के आयोजन में हमारा अभिप्राय यह नहीं होता कि पूर्व-निर्धारित निष्कर्षों की प्रामाणिकता की जाँच करें तथा उसके लिए सांख्यिकी प्रमाण प्रस्तुत करें। इसके स्थान पर परीक्षित परिणामों एवं प्रयोगों के आगामी रूपों के बीच निरन्तर सम्पर्क बना रहता है।

इस प्रकार के प्रयोगों का एक अन्य गौण उद्देश्य भी होता है जो सिद्धान्त के विकास से सम्बन्धित होता है। इस प्रकार के खेल का आयोजन करने के लिए तथा खेल में कुछ विशेषताओं को लाने के लिए पहले व्यावहारिक मान्यताओं को परिभाषित करना जरूरी होता है। इस प्रकार का खेल सैद्धान्तिक मॉडल-निर्माण पर अनुशासन कायम करता है। इसके द्वारा यह जाँच की जा सकती है कि मान्यताएँ एवं प्रस्ताव सार्थक हैं अथवा नहीं। यदि वे सार्थक हों तो उन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रयोगात्मक खेल की सैद्धान्तिक सम्प्रेषण (Theoretical Communication) के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि हम यह चाहते हैं कि संघर्ष की रणनीति

के बारे में किसी प्रस्ताव को सावधानी के साथ परिभाषित और चित्रित करें तो इसके लिए खेल के रूप में हमें एक देखने योग्य साधन प्राप्त हो जाता है।

खेल-सिद्धान्त द्वारा अनुसंधान

(The Research through Game Theory)

खेल-सिद्धान्त के आधार पर किए जाने वाले अनुसंधान में हमको तीन बातों का ध्यान रखना होता है। प्रथम, यह देखना होता है कि किन नियमों एवं प्रतिक्रियाओं के अधीन खेल-खेला जाएगा तथा इन खेल की पृष्ठभूमि क्या है और खेलने वाले लोग कौन-कौन हैं। दूसरी देखने योग्य बात यह होती है कि खेल का परिणाम क्या रहा, खिलाड़ियों का व्यवहार कैसा रहा; खिलाड़ियों द्वारा जो अभिनेत्र रगे गए वे क्या थे; खेल के दौरान जो विशेष परिस्थितियाँ विकसित हुईं वे कौन-कौन सी थी, आदि-आदि। तीसरे, यह देखना होता है कि वे प्रश्न या परिवर्तनार्थे कौन-कौन-सी हैं जिनके आधार पर नीच की निर्देशित किया जा सकता है।

प्रथम शीर्षक के अधीन वह तरीका निश्चित किया जाता है जिसके द्वारा खेल खेला जाएगा। इस तरीके का एक निश्चित रूप में प्रवर्धन किया जाता है। सर्वप्रथम तो अनेक खिलाड़ियों से युक्त खेल का एक मान्य रूप प्रयुक्त किया जाता है। इनके आधार पर खिलाड़ी खेल के परिणामों एवं खेल के रूप के बीच पारस्परिक सम्बन्ध एवं खेलने वाले की अपनी व्याख्या के परिणामों और एक-दूसरे के खेल के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। इन दृष्टि से परिणामों के वर्गीकरण एवं विवर्तण के लिए खेल के तरीकों एवं रणनीतियों के लिए तथा खेलने वालों की व्याख्याओं के लिए सैद्धान्तिक रूप से रचना करनी होती है। यह सब केवल तभी किया जा सकता है जबकि पर्याय में खेल खेला जाए। दूसरे, खेल की कुछ विशेषताओं में भिन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिए, सम्प्रेषण की व्यवस्था, सूचना की व्यवस्था, आदि में भिन्नता हो सकती है। इसके अनिर्दिष्ट खेल में प्रयुक्त किए जाने वाले नक्शे, परम्पराएँ, खेल एवं इनके लक्ष्य का वर्णन करने वाली भाषा, खेल की मायात्मक विवेचनाएँ आदि अलग-अलग प्रकार की हो सकती हैं। तीसरे, खेलने वालों के आधार पर अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। स्वयं-पूरित समूहों के बीच के खेल के लिए, विभिन्न समूहों के उन सदस्यों के बीच खेल के लिए जो पहले से ही अन्तर्मासुहिक खेल का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, अनुभवी खिलाड़ियों के बीच होने वाले खेल के लिए, अनुभवी एवं अनुभवहीन के बीच होने वाले खेल के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य खेलों के लिए व्यवस्था अलग-अलग प्रकार से करनी होती है। कुछ खेल मध्यम के अधीन खेले जाते हैं जो खेलने वालों को कुछ सुभाव दे सकता है। कुछ खेलों में तीन या तीन से अधिक खेलने वाले होते हैं; वहाँ संयुक्त व्यवहार (Coalition Behaviour) सम्भव होता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें एक खिलाड़ी को रणनीति पहले से ही स्पष्ट कर दी जाती है।

दूसरे शीर्षक के खेल-परिणामों का अभिनेत्र रखने की एक सार्यक योजना अपनायी होती है। इस योजना में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त सभी अर्थों को रखा जा

सकता है अथवा सापेक्ष रूप से रखा जा सकता है। खेल के विभिन्न प्रकारों के परिणामों की तुलना करने के लिए प्राप्त अंकों को साधारण स्तर पर रखने हेतु प्रयास करना होना है। ऐसा करना सरल नहीं होता क्योंकि इसका मार्ग कठिन होना है। उदाहरण के लिए यह जानना बड़ा कठिन होता है कि खेलने वाले ने खेल के दौरान क्या आशा की थी और उसे उसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए या नहीं। खेलने वाले की व्याख्याओं को वर्गीकृत करने के लिए भी एक योजना अपनाई जाती है। खेलने वाले खेल को जिस रूप में देखते हैं तथा खेल का जो तरीका अपनाते हैं उस पर उनको प्रदान किए गए निर्देशों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है एवं उन प्रश्नावलियों का प्रभाव पड़ता है जो वे बनाते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपनी एवं अपने भागीदार के खेल तथा रणनीतियों पर जो बातें नोट करते हैं, वे भी प्रभाव डालती हैं। खेल के सम्बन्ध में अभिलेख रखना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई अनुसन्धान कार्य नहीं किया जा सकता। अध्ययन करते समय हमारा मुख्य उद्देश्य जानकारी एवं नाजानकारी के विकास को देखना, प्रस्तावों को प्रसारित करने के लिए भाषा के आविष्कार की प्रक्रिया को जानना तथा खेल के दौरान आलोचनात्मक अवसरों को ध्यान में रखना होता है। यह भी देखा जाता है कि खेलने वाले की आशाओं का खेल में सुझाए गए विस्तारों से क्या सम्बन्ध था तथा खेलने वाले की रणनीति कितनी सही थी। पर्याप्त भूल-सुधार के बाद ही हम यह जान पाते हैं कि रोचक एवं उपयोगी अभिलेख किस प्रकार रखा जा सकता है।

जिस समय खेल हो रहा है उस समय उसे किस प्रकार देखना चाहिए तथा उसका अभिलेख किस प्रकार रखना चाहिए, इसके लिए विश्लेषणात्मक श्रेणियाँ अपनानी होती हैं। अभिलेख एवं निरीक्षण की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं, जैसे—सहयोगपूर्ण बनाम असहयोगपूर्ण, आक्रमणकारी बनाम बुद्धिपूर्ण, आदि-आदि। ये अन्तर वास्तविक व्यवहार में उपयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं और नहीं भी, इसलिए ये अपर्याप्त हैं। यह भी देखा जाता है कि क्या खिलाड़ी, उसका दूसरा भागीदार एवं खेल देखने वाला खेल के तरीकों के सम्बन्ध में एक जैसी धारणा रखते हैं और क्या इसके पीछे उनका अभिप्राय एक जैसा ही है।

तीसरे, खेल का निरीक्षण करने के बाद उसके सम्बन्ध में कुछ जाँच-पड़ताल की जाती है। जिस विशेष वस्तुस्थिति की जाँच होती है उसमें भाषा, नियमों एवं परम्पराओं का विकास सम्मिलित होता है। अस्थिरता के कारण बने तत्त्वों की विशेष रूप से जाँच की जाती है। अस्थिरता से यहाँ हमारा अर्थ खेल की उस प्रवृत्ति से है जो विध्वंसात्मक व्यवहार एवं कम अंकों का कारण होती है। प्रयोगों के आधार पर यह बात विदित हुई है कि जब नब्बे पर राज्यों के मूल्यों को पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो अधिक संघर्ष पैदा हो जाता है। यदि चाल में किए जाने वाले परिवर्तनों से समझौता तोड़ने वाले किसी खिलाड़ी को भारी लाभ प्राप्त हो जाए तो इससे अस्थिरता आ जाती है। इसके अतिरिक्त खेल की तेजी (Tempo) भी स्पष्टीकरण पर प्रभाव डालती है। खेल की विश्लेषणात्मक रचना करने के लिए

पर्याप्त भू-सुधार से काम लेना होता है। प्रयोगात्मक खेल का लक्ष्य यह नहीं होता कि स्थित परिवर्तनार्थों की गत्यता को परखा जाए बल्कि इसके द्वारा नवीन परिवर्तनार्थ निर्धारित की जाती हैं।

सौदेबाजी की विचारधारा बहुत कुछ बौद्धिक खेल-सिद्धान्त का एक विस्तार है। दोनों के तरीके प्रायः एक जैसे होते हैं तथा दोनों की मूल मान्यताएँ भी एक जैसी ही हैं। जे. सी. हर्सान्यी ने इन सिद्धान्तों की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। उनके मतानुसार बौद्धिकता की दो मान्यताएँ हैं जो मौलिक होने हुए भी कमजोर हैं- इसलिए इन मान्यताओं के साथ अन्य चार घोर जोड़ दी जाती हैं। हर्सान्यी (J. C. Harsanyi) के कथनानुसार ये छः बौद्धिक मान्यताएँ हैं—

- (1) व्यक्तिगत उपयोगिता का अधिकार (Individual Utility Maximization),
- (2) कार्यकुशलता (Efficiency),
- (3) उच्च क्षतिपूर्ति की स्वीकृति (Acceptance of Higher Pay-off),
- (4) प्रतिमाम्य (Symmetry),
- (5) परिवर्तनियों का प्रतिबन्ध (Restriction of Variables), तथा
- (6) पारस्परिक रूप में प्रामाण्यित बौद्धिकता (Mutually Expected Rationality)।

इन मान्यताओं के बीच कितना तार्किक सम्बन्ध है, यह एक विवाद का विषय है।

खेल-सिद्धान्त का मूल्यांकन (Evaluation of Game Theory)

खेल-सिद्धान्त का व्यावहारिक दृष्टि से अर्थ है महत्त्व है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को समझने के लिए केवल बौद्धिक चिन्तन की परिधि में विचारकों को बाहर निकालता है तथा उनको व्यावहारिक निरीक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने के अवसर प्रदान करता है। इसके मुख्य उपयोग निम्न प्रकार हैं—

1. जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विश्वयुद्ध के बाद स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित हो गई तो इन गुटों के बीच बहुत कुछ ऐसा ही खेल-मेला गया था जैसा कि खेल-सिद्धान्त के प्रयोगों में खेला जाता है। नाटो शक्तियाँ, साम्यवादी शक्तियाँ एवं तटस्थ शक्तियाँ—ये इस खेल के तीन खिलाड़ी थे। यदि इस खेल का विश्लेषण किया जाए तो हम अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होंगी जिनकी बाद में हम मैथानिक प्रतिमा (मॉडल) के रूप का आधार बना सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय-राजनीति में इस सिद्धान्त की महत्वपूर्ण मानने वालों का यह दावा है कि तथ्यपूर्ण रूप में जितनी सूचना खेल से प्राप्त हो सकती है वह साहित्यिक विश्लेषण द्वारा कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। साहित्यिक विश्लेषण से प्राप्त सूचना को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता।

2. खेल-सिद्धान्त की यह विशेषता है कि इसके आधार पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय घटना का विश्लेषण करने के बाद दूसरी अन्य घटनाओं को समझने का मार्ग खुल जाता है।

3. यह सिद्धान्त अनुभव पर आधारित (Empirical) है, इस कारण इसमें भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं, समस्या के लिए समाधान ढूँढे जा सकते हैं।

उक्त लाभों को स्वीकार करते हुए भी खेल-सिद्धान्त के समर्थक यह मानते हैं कि विश्व की जटिल समस्याओं पर अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। दूसरे कुछ विचारकों द्वारा खेल-सिद्धान्त को केवल मात्र खेल की दृष्टि से ही देखा जाता है अर्थात् विद्वानों में यह सिद्धान्त कोई गम्भीर समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। अधिकांश के विचार से गम्भीर, सश्लिष्ट तथा उलझी हुई अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ इस सिद्धान्त द्वारा नहीं समझी जा सकती। क्विंसी राइट (Quincy Wright) का मत है कि यदि हम शीतयुद्ध का विश्लेषण इस सिद्धान्त के आधार पर करें और तब अपने देश की विदेश-नीति का निर्धारण करें तो वह नीति न तो विजय प्राप्त करा सकेगी और न ही हमें निष्पक्ष रख सकेगी वरन् यह तो देश की पूरी हत्या का कारण बन जाएगी, ऐसी हत्या जिसे उसने स्वयं ही चुना है।

खेल-सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने का एक अपूर्ण माध्यम है। इसमें समय तथा शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उनकी तुलना में इससे प्राप्त होने वाले परिणाम नगण्य रह जाते हैं। इस सिद्धान्त को अपनी कुछ समस्याएँ भी हैं जिनके कारण इसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में लागू नहीं किया जा सकता। अनेक विद्वान् इसे वैज्ञानिक मानने को भी तैयार नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामान्य विचारधारा (General Theory in International Field)

सामान्य विचारधारा वह होती है जो समान परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर सभी देशों द्वारा अपनाई जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में सामान्य सिद्धान्तों का परिणाम अधिक नहीं है। सम्भवतः इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के ऊपर समय-समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा विचार प्रकट किए जाते हैं, किन्तु ये विचार इतने एकपक्षीय तथा सीमित होते हैं कि इनके माध्यम से स्थिति के पूर्ण रूप को नहीं समझा जा सकता। इन एकपक्षीय सिद्धान्तों में सामर्थ्य नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के वास्तविक व्यवहार का चित्र प्रस्तुत कर सकें। भूतकाल में इन सिद्धान्तों का निर्माण एक विशेष हित रखने वाले समुदाय के लिए किया जाता था जैसे सैनिक समुदाय, वूटनीतिज्ञ, न्यायिक (Jurist), क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी, साम्राज्यवादी, शान्तिवादी, शिक्षक तथा अन्य। क्विंसी राइट के मतानुसार क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ के लिए प्रतिपादित सिद्धान्तों का शान्तिवादी व अन्तर्राष्ट्रीयतावादी लोगों के लिए कोई महत्त्व नहीं होगा। इन सिद्धान्तों के निर्माता भी इतिहासकार, भूगोलशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, नीतिशास्त्री आदि थे। उन्होंने

केवल विशिष्ट तथा संकुचित दृष्टिकोण से ही वस्तुस्थिति को परखा घोर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सम्पूर्ण चित्र को अंकित करने में सफल नहीं हो सके।

आजकल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सामान्य सिद्धान्त की आवश्यकता को कई दृष्टियों से स्वीकार किया जा रहा है। कहा जाता है कि सामान्य सिद्धान्त राजनीतिज्ञों की सहायता करेगा। जिन लोगों को विदेश-नीति के सम्बन्ध में निर्णय लेने होते हैं उनके पास प्रदर्शक के रूप में एक ऐसे सिद्धान्त का होना आवश्यक है जो उनके लक्ष्य तथा साधनों की समुचित व्याख्या कर सके। राजनीति घण्टा निर्णायकता (Decision-maker) के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कूटनीतिज्ञों, मंत्रियों, कानूनवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों, उपनिवेशीय प्रशासकों, अन्तर्राष्ट्रीय लोकसेवकों आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का कार्य है कि इन सभी को सुविज्ञ-परामर्श (Expert Advice) प्रदान करे। इसके अतिरिक्त सामान्य सिद्धान्त (General Theory) का एक महत्वपूर्ण कार्य है नागरिकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का समुचित ज्ञान कराना। आज प्रजातन्त्र का युग है तथा प्रत्येक व्यक्ति विदेश-नीति के निर्णयों पर अपना प्रभाव डालना चाहता है, किन्तु कोई प्रभाव डालने से पूर्व आवश्यक है कि व्यक्ति को उस विषय का ज्ञान हो। सामान्य सिद्धान्तों का एक सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शोध-कार्य को आसान बना देता।

सामान्य सिद्धान्त का अर्थ व स्वरूप

सामान्य सिद्धान्त का अर्थ बताते हुए क्विंसी राइट ने लिखा है कि यह ज्ञान का वह रूप है जो विस्तृत, समझने योग्य, समृद्ध तथा आत्म-शोधक हो तथा इससे जानकारी, भविष्यवाणी, मूल्यांकन, विश्व के राज्यों के आपसी सम्बन्धों तथा विश्व की परिस्थितियों के नियन्त्रण को कुछ योगदान मिल सके।¹ क्विंसी राइट ने विचारानुसार दस सप्तर गुरों से युक्त सिद्धान्त को प्राप्त करना सर्वथा असम्भव है।

क्विंसी राइट की परिभाषा में प्रकृति एवं उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य सिद्धान्त की जिन विशेषताओं का सकेत किया गया है वे निम्नलिखित हैं—

सामान्य सिद्धान्त की प्रकृति एवं उद्देश्य

सामान्य सिद्धान्त में किसी एक विषय की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सभी पहलुओं पर विचार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, शान्तिपूर्ण एवं युद्ध-सम्बन्धी, सहकारितापूर्ण व परस्पर विरोधी, सार्वभौमिक तथा क्षेत्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि। सामान्य सिद्धान्त उलभा हुआ घोर विस्तृत नहीं होना चाहिए। विस्तृत सिद्धान्त प्रायः उलभनपूर्ण होता है और उलभन के कारण वह अपने गुरों से वंचित रह जाता है जिनकी उससे आशा की जाती है। यह ऐसे सामाजिक व्यवस्थाओं में अभिव्यक्त किया गया हो जो

समझ में आने योग्य हों, संगठित हों तथा कम से कम हो। मूल बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहने की अपेक्षा उसे उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। अत्यधिक संक्षेप भी कई बार अस्पष्टता का कारण बन जाता है, किन्तु फिर भी आवश्यकता से अधिक स्पष्टीकरण में विरोधाभास या असंगतियाँ पैदा होने का डर रहता है।

सामान्य सिद्धान्त के निष्कर्ष किसी ताकिक विश्लेषण के सहज एवं स्वाभाविक परिणाम होने चाहिए। इसका प्रत्येक भाग एक दूसरे से सम्बन्धित तथा समायोजित हो तथा उनमें परस्पर विरोध न हो। इसके अतिरिक्त सामान्य सिद्धान्त में स्वयं की कमियों को पूरा करने तथा स्वयं के दोषों को दूर करने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में किसी का यह सोचना गलत होगा कि उसके निष्कर्ष अन्तिम सत्य है तथा हमेशा ही रहेंगे, यह आवश्यक है कि समय एवं परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही उनके रूप में यथोचित परिवर्तन कर दिए जाएँ।

सामान्य सिद्धान्त का प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह जनता और राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में बहुत समय पहले से जमे हुए उन विचारों को खुरच दे जिनका आज की परिस्थितियों में कोई महत्त्व नहीं रह गया है। इसके अध्ययन का रूप वस्तुपरक (Objective) होना चाहिए क्योंकि मत्प एव तथ्य की पूर्णता के लिए ऐसा होना जरूरी है। इस अर्थ में सामान्य सिद्धान्त का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी कार्य है जो सशोल शास्त्र के क्षेत्र में कागरनिक्स ने किया था। सामान्य सिद्धान्त को ऐसे भागों को प्रदर्शित करना चाहिए जिनमें भविष्य के शोधकर्त्ता तथा अध्ययनकर्त्ता आगे बढ़ सकें और इस क्षेत्र में अपना अनुदान प्रदान कर सकें। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नवीन विचारों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वे भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने हमारे स्वयं के। नवीन विचारों के सन्दर्भ में यदि समय-समय पर अपने मतों एवं धारणाओं को भी सशोधित कर लिया जाए तो उचित रहेगा।

2. अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का दूसरा लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भविष्यवाणी करने के कार्य को सम्भव बनाना है। इसके लिए यह जरूरी है कि कारण-कार्य सम्बन्ध को उचित रूप से बँटाया जाए। इसका स्वरूप वैज्ञानिक होना चाहिए। 'इन परिस्थितियों के होने पर यह कार्य होगा' अथवा 'ऐसा' करिए, ऐसा हो जाएगा' आदि कहने की सामर्थ्य इनमें होनी चाहिए, किन्तु प्रायः यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में सम्भव नहीं हो पाता। इसके अनेक कारण हैं जैसे कि मानवीय व्यवहार एकसा नहीं होता, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की तुलना नहीं की जा सकती, हम अपनी परिकल्पनाओं पर प्रयोग नहीं कर सकते, आदि। फिर भी कुछ बातों पर कुछ मात्रा में भविष्यवाणी की जा सकती है और हमें अवश्य ही इस प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।¹

3. अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सिद्धान्त का तीसरा लक्ष्य परिस्थिति का मूल्यांकन करना है। इसका यह कार्य है कि आवश्यकता के समय लोगों को केवल तथ्यों का

ज्ञान कराने की अपेक्षा यह भी बताए कि उनके लिए अच्छा क्या है। इसी धर्म में प्लेटो कहा करता था कि समय पर राजनीतिज्ञ को सज्जनतापूर्ण भूठ (Noble lies) भी बोल देना चाहिए। इस दृष्टि से सत्य का मापदण्ड प्रमाण प्रयत्न दुर्द्धि नहीं है वरन् इसका व्यावहारिक प्रयोग है। हमें जनता से जो कराना है तथा जिन सिद्धान्तों को ग्रहण कराना है उनका उद्देश्य बताते समय कूटनीति से बच लेना आवश्यक हो जाता है। सामान्य जनता बालक-बुद्धि से बाध करती है। यदि बालक से भाष्य करें कि "वह अध्ययन में रुचि ले, इससे व्यक्तित्व का विकास होगा" तो इस कथन का व्यावहारिक प्रभाव इनका न होगा जिनका कि यह कहने पर कि "वह अध्ययन करेगा तो उसे मिठाई व खिलौने दिए जाएंगे।" यद्यपि दोनों परिस्थितियों में अध्ययन का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास ही है। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के अध्ययन का विषय है मनुष्य तथा उसके समुदाय। मनुष्यों के जीवन के कुछ मूल्य होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सिद्धान्तों को उन मूल्यों के समायोजन में ही अपने सदस्यों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए वरना मनुष्य जिन मूल्यों को महत्व देना है उनकी सुरक्षा के लिए वह सिद्धान्तों को नितान्जलि दे सकता है। कुछ विचारकों का मन है कि समाज-विज्ञानशास्त्रियों को केवल तथ्यों व प्रमाणों में मध्यस्थ रहना चाहिए 'मूल्यों' से नहीं, किन्तु स्विस्सी राइट के मतानुसार सामाजिक विज्ञान 'मूल्यों' की अवहेलना नहीं कर सकते, यह तो इनका मूल तत्त्व होगा।

4. अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त को यह बताना चाहिए कि क्या होने को है; यह भी बताना चाहिए कि क्या होना अच्छा है तथा साथ ही सरकार व जनता के लिए जो अच्छा है उसे कायम रखने के लिए निर्णय लेने में सहायता देनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर सरकारें तब तक नियन्त्रण नहीं रख सकती जब तक उन्हें भाफ-भाफ यह पता न हो कि वे ऐसा क्यों करना चाहती हैं। कोई निर्णय लेने में पूर्व हमारे सामने कुछ मूल्यों का रहना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार के मूल्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं।

5. अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण कार्य आज यह है कि विश्व-समुदाय की परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए प्रयास करें। आज का युग सम्प्रभु राष्ट्रीय राज्यों की स्थिति में परिवर्तन की माँग करता है। वह विश्व-भारकार की स्थापना चाहता है। सामान्य सिद्धान्तों का यह कर्तव्य बन जाता है कि समय की इस आवश्यकता व युग की इस माँग को ध्यान में रख कर ही आगे बढ़े।

उपर्युक्त उद्देश्यों एवं तत्त्वों को अपने-आप में प्रारण करने वाला कोई अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त हो सकेगा, ऐसी आशा नहीं है। उपर्युक्त सभी विशेषताएँ एक आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का चित्रण करती हैं। सिद्धान्तशास्त्रियों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे अपने सिद्धान्तों में इन विशेषताओं को अधिक से अधिक समाविष्ट करें। कोई भी सिद्धान्त इन विशेषताओं के जितना नजदीक होगा वह उतना ही उपयोगी, श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक माना जाएगा।

यथार्थवादी सिद्धान्त (The Realistic Theory)

हम बता चुके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त के रूप में मान्यता पाने के क्षेत्र में राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद दो प्रमुख प्रतियोगी हैं।¹ आदर्शवाद का दर्शन 18वीं और 19वीं शताब्दियों में काफी प्रचलित था तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद इसे पुनर्जीवन मिला। आज विख्यात राजनीतिशास्त्री हंस मॉर्गेंथो यथार्थवादी सिद्धान्त के प्रमुख प्रवक्ता है। यद्यपि यथार्थवाद के क्षेत्र में और भी अनेक विद्वानों का योगदान है, तथापि मॉर्गेंथो को ही इस बात का वास्तविक श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने यथार्थवाद को एक सिद्धान्तिक अनुस्थापन (Theoretical Orientation) प्रदान किया। हंस मॉर्गेंथो को ही श्रेय है कि उन्होंने सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण को चिन्तन के एक पृथक् और स्पष्ट सम्प्रदाय का रूप दे दिया। यथार्थवाद पर अनेक लेखकों ने लिखा है, अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मॉर्गेंथो ही वह प्रथम विद्वान् हैं जिसने एक यथार्थवादी प्रतिमान (A Realistic Model) विकसित किया है। इस क्षेत्र के मॉर्गेंथो के महान् योगदान को स्वीकार करते हुए ही अनेक विद्वान् 'यथार्थवाद' और 'मॉर्गेंथोवाद' को समानार्थी मानते हैं।

मॉर्गेंथो की मान्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार 'शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा' (Concept of Interest Defined in Terms of Power) है। यह दृष्टिकोण हमारा ध्यान उन इकाइयों पर अर्थात् राज्यों पर, जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, केन्द्रित कर देती है। इसे यथार्थवादी दृष्टिकोण की सजा इसलिए दी जाती है क्योंकि एक तो यह राष्ट्रीय हित के महत्त्व पर उसी रूप में बल देती है जिस रूप में किसी राष्ट्र-विशेष के राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय हित को मान्यता देते हैं; और दूसरे, यह शक्ति अथवा प्रभाव (Power or Influence) को राष्ट्रीय हित के सन्दर्भन का एकमात्र साधन मानती है। जिस सीमा तक इसमें शक्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, उस सीमा तक इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण (Power Approach) भी कहा जा सकता है। मॉर्गेंथो ने स्पष्ट लिखा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्य सभी राजनीतियों की तरह, शक्ति के लिए संघर्ष है और चाहे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्तिम उद्देश्य कुछ भी हो, इसका तात्कालिक लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना ही रहता।"² अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थता को समझने के लिए शक्ति की महत्ता तथा व्यावहारिकता को समझना नितान्त आवश्यक है। शक्ति को परिभाषित करते हुए एक अन्य स्थल पर

1 George F. Kennan : American Diplomacy (1900-50)

2 "International Politics, like all politics, is a struggle for power, whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim"

—Hans J. Morgenthau : Politics Among Nations, p. 2

मॉर्गेन्थो ने लिखा है कि 'यह अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्कों और कार्यों पर मनुष्य का नियन्त्रण' (Man's control over the minds and actions of other men) है।

मॉर्गेन्थो के पूर्ववर्ती और परवर्ती अनेक विचारकों ने शक्तिवादी दृष्टिकोण पर बल दिया है। उदाहरणार्थ, 19वीं शताब्दी में ट्रीट्स्के (Treitschke) और नीत्शे (Nietzsche) ने शक्ति के विचार और शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा की भारी बकालत की। प्रथम महायुद्ध से पूर्व एरिख कॉफ़मैन (Erich Kaufmann) ने एक पुस्तक लिखी जिसमें बताया कि शक्ति के विकास, सवर्द्धन और प्रदर्शन (Machtentfaltung) में ही राज्य का सार है। कॉफ़मैन ने एक विश्व-राज्य की अवधारणा को इस आधार पर ठुकरा दिया कि ऐसी अवधारणा में शक्ति के विकास-सवर्द्धन-प्रदर्शन की आवश्यकता का अभाव पाया जाएगा जबकि यह बात एक राज्य का आवश्यक तत्त्व है। फ्रांज़िस्क बाल्कस, हेरॉल्ड सासवेल, डेविड ईस्टन आदि ने भी राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी विचारधारा के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया है, इन सभी का 'शक्ति-राजनीति' (Power Politics) पर आग्रह है। डेविड ईस्टन ने राजनीति-विज्ञान को 'मूल्यों के सत्तात्मक आवरण का अध्ययन' माना है क्योंकि "यह शक्ति के प्रयोग और वितरण से प्रभावित होता है।"¹ मॉर्गेन्थो के समान ही ई एच कार, क्विंसी राइट, जॉर्ज श्वार्ज़न बर्गर, मार्टिन वाइट आदि आधुनिक विचारक भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में राजनीति-विज्ञान की 'शक्ति' सम्बन्धी अवधारणा के विस्तार के समर्थक हैं। पर इन सभी में मॉर्गेन्थो ही एक विद्वान् है जिसने 'शक्ति' के दृष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों अथवा राजनीति पर सबसे अधिक व्यवस्थित काम किया है। अन्य विद्वानों ने मॉर्गेन्थो द्वारा स्थापित परम्परा को ही आगे बढ़ाया है अथवा मॉर्गेन्थो द्वारा प्रतिपादित विचारों में अपनी व्याख्याएँ जोड़ी हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद को समझने के लिए मॉर्गेन्थो के यथार्थवादी सिद्धान्त² को समझना परमावश्यक है।

मॉर्गेन्थो के दार्शनिक आधार

(Philosophical Basis of Morgenthau)

मॉर्गेन्थो ने अपना विख्यात यथार्थवादी सिद्धान्त अपने ग्रन्थ 'राष्ट्रों के मध्य राजनीति' (Politics Among Nations) में प्रकट किया है। उनकी मान्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के किसी भी सिद्धान्त की परीक्षा की कसौटी अमूर्त न होकर अनुभववादी और व्यावहारिक (Empirical and Pragmatic) होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सिद्धान्त का निर्णय किसी पूर्व-निश्चित अमूर्त विचार

1 David Easton : The Political System, p. 146.

2 Hans J. Morgenthau : Ibid, pp. 3-14.

अथवा वास्तविकता से असम्बद्ध धारणा से नहीं किया जाना चाहिए वरन् उसके उद्देश्य से (By Its Purpose) किया जाना चाहिए। माँगेंथो के अनुसार उनके द्वारा प्रनिपादित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धान्त समस्त राजनीति की प्रकृति (The Nature of all Politics) से सम्बन्धित है। आधुनिक राजनीतिक चिन्तन का इतिहास उन दो प्रणालियों अथवा विचारधाराओं के बीच संघर्ष की कहानी है जो मनुष्य, समाज और राजनीति की प्रकृति से सम्बन्धित अपनी अवधारणाओं में एक दूसरे से मौलिक रूप में भिन्न हैं। यहाँ माँगेंथो का संकेत आदर्शवादी तथा यथार्थवादी अवधारणाओं से है। आदर्शवादी सिद्धान्त पूर्वकल्पित अमूर्त सिद्धान्तों और मान्यताओं पर आधारित होता है जिसका वास्तविक जगत् की घटनाओं से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता, अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के कोरे आदर्शों से काम नहीं चलता कि चूँकि मानव-प्रकृति विवेकशील है और उसमें सहिष्णुता तथा आदर्श के प्रचुर तत्त्व विद्यमान हैं, अतः मानव के व्यवहार में जो भी त्रुटियाँ दिखाई देती हैं उन्हें उचित कारणों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार से दूर किया जा सकता है अथवा यदि बहुत ही अनिवार्य हो जाए तो यदाकदा शक्ति के प्रयोग द्वारा मनुष्य को सही मार्ग पर लाया जा सकता है। इस प्रकार का विश्वास कोरी कल्पना है कि सर्वमान्य अमूर्त सिद्धान्तों से उद्भूत विवेकपूर्ण और नैतिक राजनीतिक व्यवस्था यही और अभी (Here and Now) प्राप्त की जा सकती है।

माँगेंथो ने वास्तविकता अर्थात् यथार्थ का समर्थन किया है। उनकी मान्यता है कि यह विश्व विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से जिस रूप में अपूर्ण है उस रूप में वह मानव-प्रकृति में अन्तर्निहित सहज शक्तियों (Forces) का परिणाम है और ऐसे विश्व को सुधारने के लिए इन शक्तियों के साथ सहयोग करके चलने से ही लाभ है, इनके विरुद्ध चलने या इनकी अवहेलना करने से नहीं। चूँकि यह संसार परस्पर विरोधी हितों और उनके बीच टकराव का प्रकट स्वरूप है, अतः इसमें नैतिक सिद्धान्तों का पूरी तरह अनुसरण नहीं किया जा सकता। यह सम्भव है कि इन परस्पर विरोधी हितों के मध्य अस्थायी रूप से सन्तुलन स्थापित कर तथा संघर्षों को यथासम्भव कम कर नैतिक सिद्धान्तों का यथासाध्य पालन करने का प्रयत्न किया जाए। वास्तविकता यह है कि विश्व एक बहुल समाज है जिसमें नियन्त्रण तथा सन्तुलन से ही व्यवस्था कायम रह सकती है। चूँकि सर्वोत्तम को प्राप्त करना असम्भव है, अतः जहाँ तक हो सके सुराई को कम करना ही उचित है। यथार्थवादी सिद्धान्त का यही दार्शनिक आधार है।

राजनीतिक यथार्थवाद के छः सिद्धान्त (Six Principles of Political Realism)

राजनीतिक यथार्थवाद को समझने और उस पर अमल करने के लिए माँगेंथो ने छः नियम प्रतिपादित किए हैं जो इस प्रकार हैं—

पहला सिद्धान्त—राजनीतिक यथार्थवाद का विश्वास है कि सामान्यतः

समाज की भाँति राजनीति भी उन यथार्थवादी ग्रथवा दस्तुपरक नियमों (Objective Laws) से अनुशासित होती है जो मानव-प्रकृति में निहित हैं। समाज को सुधारने के लिए आवश्यक है कि पहले उन नियमों को समझ लिया जाए जो समाज के जीवनाधार हैं। इन नियमों की प्रक्रिया पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, अतः यदि इन्हें चुनौती दी गई तो इसमें हमारी ही हानि तथा असफलता की सम्भावना अधिक है। यथार्थवाद राजनीति के प्रत्यक्ष स्वरूप को महत्व देता है, अतः इसका विश्वास है कि एक ऐसे विवेकपूर्ण सिद्धान्त (A Rational Theory) का विनिर्माण किया जा सकता है जो इन दस्तुपरक नियमों को प्रतिबिम्बित करे और जितके द्वारा हमारे लिए यह जानना सम्भव हो जाए कि राजनीति के प्रकट स्वरूप में सच्चाई का कितना पुट है और व्यक्ति के काल्पनिक सिद्धान्तों ने राजनीति को यथार्थ से कहीं तक दूर कर दिया है।

मॉगेंथो का मत है कि मानव-प्रकृति, जिसमें राजनीति के नियम सन्निहित हैं, प्राचीन काल से अभी तक मूल रूप में बदली नहीं है, अतः इतिहास द्वारा प्रस्तुत प्रमाणाँ के सन्दर्भ में वर्तमान राजनीतिक घटनाओं का मूल्यांकन करना विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से सर्वथा सम्भव है। उन विकल्पो का, जो अतीत के इतिहास में उत्पन्न तत्कालीन समस्याओं के समाधान में कारगर सिद्ध हुए थे, आज भी उतना ही महत्व है। इतिहास में शक्ति-सन्तुलन का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का बड़ा उपयोगी आधार रहा है और आज भी उसका महत्व है। शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त को केवल यह कह कर नहीं ठुकराया जा सकता कि वह अब पुराना पड़ गया है। उचित यही है कि हम प्रत्येक सिद्धान्त को सदैव विवेक और अनुभव की कसौटी पर परखें और उसका बहिष्कार तभी करें जब वह कसौटी पर खरा न उतरे। यथार्थवाद यह मानकर चलता है कि तथ्यों का मूल्यांकन करने और विवेक द्वारा अर्थ प्रदान करने में ही एक सिद्धान्त का समुचित अस्तित्व है। यथार्थवादी सिद्धान्त की धारणा है कि विदेश-नीति के स्वरूप को हम तभी समझ सकते हैं जब किए गए राजनीतिक कार्यों और इन कार्यों के सम्भावित परिणामों का मूल्यांकन कर लिया जाए। तभी हम यह जान सकते हैं कि राजनीतिज्ञों ने वास्तव में क्या किया है और उनके कार्यों के सम्भावित परिणामों से यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उनके उद्देश्य क्या थे।

लेकिन केवल तथ्यों के संकलन से ही विदेश-नीति का मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता। विदेश-नीति की तथ्य सम्बन्धी सामग्री को अर्थ प्रदान करने के लिए हमें राजनीतिक यथार्थता की एक प्रकार की तार्किक दृष्टि से जाँचना होगा—इस प्रकार देखना होगा जो हमें विदेश-नीति का सम्भावित अर्थ ज्ञात हो सके। दूसरे शब्दों में, हमें स्वयं को उस राजनीतिज्ञ के स्थान पर रखना होगा जिसे अवस्था-विशेष में विदेश-नीति की समस्या-विशेष का सामना करना है और हमें स्वयं से पूछना होगा कि वे बौद्धिक ग्रथवा विवेकपूर्ण विस्तृत क्या हैं जिनमें से वह राजनीतिज्ञ, जिसे समस्या का उन्ही अग्रवाधों में सामना करना है, चुनाव (यह अनुमान लगाते हुए

कि उस राजनीतिज्ञ का व्यवहार विवेकपूर्ण ही होगा) करना चाहेगा। इस विवेकपूर्ण कल्पना को वास्तविक तथ्यों की कसौटी पर कसने से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्य समुचित रूप से अर्थपूर्ण हो सकेंगे और राजनीति के एक सिद्धान्त का निर्माण हो सकेगा।

दूसरा सिद्धान्त—राजनीतिक यथार्थवाद की दूसरी प्रमुख मान्यता है 'शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा' (Concept of Interest Defined in Terms of Power) अर्थात् राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए शक्ति का प्रयोग। माँगेंथो के अनुसार यह एक ऐसा विचार है जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथ्यों और उन्हें समझने वाले विवेक के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। हित वा केन्द्र-बिन्दु सुरक्षा है और सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित की जाती है। दूसरे शब्दों में हित की कल्पना शक्तिविहीन सन्दर्भ में नहीं की जा सकती। राजनीति का मुख्य आधार हित और उनकी सुरक्षा है और इसीलिए हम राजनीति को भी शक्ति से अलग रख कर नहीं समझ सकते। तात्पर्य यह है कि शक्ति राजनीति का केन्द्र-बिन्दु है और इस आधार पर हम किसी भी आन्तरिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतन्त्र विषय मानकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। माँगेंथो की मान्यता है कि विदेश-नीति-निर्माता राजनीतिज्ञ शक्ति को, जो राजनीति की केन्द्र-बिन्दु है, आधार मानकर ही नीतियों की रचना करते हैं और इतिहास भी इसी बात की पुष्टि करता है।

इतिहास के उदाहरणों को देखने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ 'शक्ति के रूप में परिभाषित हित' की दिशा में ही सोचता और कार्य करता है। इस आधार पर हम यह मान सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिज्ञों द्वारा जो कुछ कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं या उठाए जाएंगे वे 'हित अथवा स्वार्थ' (Interest) साधन की दिशा में ही होंगे। राजनीतिज्ञ जो भी बोलता, सोचता अथवा लिखता है, उसे समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह सब करते समय उसका उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना है और इसी ढंग से हम उसकी क्रियाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। 'शक्ति के रूप में परिभाषित हित' के आधार पर ही हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को सिद्धान्तिक रूप प्रदान कर सकते हैं। यही एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर राष्ट्रों की विदेश-नीतियों में निरन्तरता का आभास मिलता है चाहे इनका निर्माण करने वाले समय-समय पर बदलते रहे हों और उनके बौद्धिक स्तर, उद्देश्य, नैतिक गुण आदि भिन्न-भिन्न रहे हों। इस दृष्टि से यथार्थवादी सिद्धान्त को अपने आपको दो भ्रान्तियों से बचाए रखना चाहिए—एक, मंतव्यों से सम्बन्धित भ्रान्ति से (The Concern with Motives) तथा दूसरी, वैचारिक वरीयताओं से सम्बन्धित भ्रान्ति से (The Concern with Ideological Preferences)।

यदि हम राजनीतिज्ञों के मतव्यो (Motives) को देखकर ही किसी देश की विदेश-नीति को समझने का प्रयास करेंगे तो असफल रहेंगे और धोखा खाएंगे।

मंतव्य अथवा प्रयोजन (Motives) एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चीज है जिसका रूप कर्त्ता और दर्शक (Actor and Observer) दोनों के हितों और भावनाओं से प्रभावित होता रहता है। हम स्वयं अपने ही प्रयोजन को समझने में भूल कर जाते हैं तो फिर दूसरे की तो बात ही क्या है।

मॉर्गेंथो का मत है कि राजनीतिज्ञों के वास्तविक प्रयोजनों (Real Motives) के आधार पर ही हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि उनकी विदेश-नीतियाँ नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय तथा राजनीतिक दृष्टि से सफल रहेगी। इन्होंने प्रयोजनों के गुण और विदेश-नीति के गुण में कोई सही तथा आवश्यक सहसम्बन्ध (Exact and Necessary Correlation) स्थापित नहीं करता। विश्व-शान्ति और भ्रातृत्व की भावना का उद्देश्य लेकर चलने वाली नेहरूवादी विदेश-नीति को प्रपचार्यवादी कहकर आलोचना का विषय बनाया जाता है। चैम्बरलेन की तुष्टिकरण की विदेश-नीति का उद्देश्य था समार में शान्ति स्थापित रखना, किन्तु धाज का विद्यार्थी जब द्वितीय महायुद्ध के कारणों का अध्ययन करता है तो यह नीति आलोचना का पाय बनती है। दूसरी ओर विन्स्टन चर्चिल की विदेश-नीति का प्रयोजन मानव-वत्प्राण की अपेक्षा सजीवों स्वार्थ था, लेकिन उसके परिणाम चैम्बरलेन की शान्तिवादी नीति के परिणामों की अपेक्षा अधिक नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिक उच्चस्तर के समझे गए। अभिप्राय यह है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण किसी कार्य का नैतिक तथा राजनीतिक स्तर उसके प्रयोजनों में नहीं बल्कि उसके परिणामों में देखा जाता है। एक उचित राजनीतिक सिद्धान्त वह है जो राजनीतिज्ञ के प्रयोजनों या अभिप्रायों की अपेक्षा उसके विवेक, संकल्प और उनकी क्रियाशीलता के राजनीतिक स्तर पर निश्चित हो। यथार्थवादी सिद्धान्त विदेश-नीति के मूल्यवर्णन का एक ऐसा आधार प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा अविवेकपूर्ण प्रभावों का सही अनुमान लगाया जा सकता है।

मॉर्गेंथो के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धान्त अपने आपको इस प्रचलित भ्रान्ति से दूर रखता है कि हम एक राजनीतिज्ञ की विदेश-नीति और उसकी दार्शनिक तथा राजनीतिक सहानुभूति को एक ही मान लें। विदेश-नीति को यथार्थ रूप से समझने के लिए यह देखना आवश्यक नहीं है कि एक राजनीतिज्ञ की दार्शनिक एवं राजनीतिक सद्भावनाएँ किसके साथ हैं। धाज के अन्तर्राष्ट्रीय जगत में यह एक सामान्य परम्परा-मी बन गई है कि प्रत्येक देश अपनी विदेश-नीति को सिद्धान्तिक धारण पहना कर आकर्षक बना देता है ताकि युवा-जनमत उसकी ओर खिंचता चला जाए। साम्यवादी चीन यथार्थ रूप में विस्तारवादी और सैन्यवादी नीति पर आचरण कर रहा है, किन्तु वैदेशिक क्षेत्र में अपने आपको पञ्चशील का समर्थक, सहप्रवर्तक का पालक और पूँजीवादी शोषण को मिटाने वाला घोषित करता है और एशिया तथा अफ्रीका के कुछ देश उसके मायावी रूप की ओर आकर्षित भी हो गए हैं।

राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक आदर्शों और नैतिक सिद्धान्तों का विरोधी

नहीं है। वह स्वीकार करता है कि इन बातों का भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में कुछ न कुछ महत्त्व है। लेकिन यह समझ लेना निरान्त आवश्यक है कि एक देश जो करना चाहता है और जो कर रहा है—इन दोनों के बीच बहुत भारी अन्तर रहता है अर्थात् 'कथनी' और 'करनी' में बड़ा फर्क पाया जाता है। हर जगह और हर समय जो कार्य हमें करने चाहिए (Desirable) तथा एक स्थान-विशेष और समय-विशेष में क्या किया जा सकता है (Possible)—इन दोनों बातों में भारी अन्तर रहता है जिसकी अवहेलना यथार्थवादी सिद्धान्त नहीं कर सकता। यथार्थवादी विदेश-नीति एक आदर्श है जिसको यथासम्भव प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब वास्तविक विदेश-नीति को आदर्श के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और वास्तविकता में से अयथार्थवादी तत्त्वों को निकालने का प्रयत्न किया जाए।

मॉर्गेंथो के अनुसार राजनीतिक यथार्थवाद केवल एक सैद्धान्तिक विचार ही नहीं है अपितु एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नीतियों में यथासम्भव विवेकपूर्ण तत्त्वों का समावेश हो और जहाँ तक हो सके अविवेकपूर्ण भ्रान्तियों और भटकावों से बचा जाए। विवेकपूर्ण विदेश-नीति ही श्रेष्ठ विदेश-नीति होती है क्योंकि वह हानि की सम्भावनाओं को कम करती है तथा लाभ की सम्भावनाओं को बढ़ाती है। राजनीतिक यथार्थवाद एक विवेकपूर्ण नीति की सैद्धान्तिक रचना प्रस्तुत करता है जिसे कोरा अनुभव कभी पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकता। यथार्थवादी विदेश-नीति का आधार नैतिक भी होता है और साथ ही इसमें सफलता के लिए राजनीतिक आवश्यकताओं का समावेश भी होता है।

तीसरा सिद्धान्त—यथार्थवादी राजनीति के तीसरे नियम के अनुसार शक्ति नाम से परिभाषित हित का कोई ऐसा अर्थ नहीं है जो सदैव के लिए अपरिवर्तनीय हो। हित का विचार वस्तुतः राजनीति का एक गूढ़ तत्त्व है जिस पर परिस्थितियों, स्थान और समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी इतिहास के किसी भी युग में राजनीतिक कार्यों का स्वरूप तत्कालीन परिस्थितियों से अवश्य ही किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। इस प्रकार मॉर्गेंथो के अनुसार हित दो प्रकार के होते हैं—अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। राजनीति का गूढ़ तत्त्व सुरक्षा में निहित है जिसके बिना न तो किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व रह सकता है और न किसी राष्ट्र का। सुरक्षा किसी भी राष्ट्र का न्यूनतम कार्य है। यह सुरक्षा ही वह अपरिवर्तनीय हित है जो कभी नहीं बदलता। किन्तु इस हित को चरितार्थ करने के साधनों और उससे सम्बन्धित हितों पर राजनीति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है तथा उनका स्वरूप परिस्थितियों के अनुकूल बदलता है। सुरक्षा हेतु अपना प्रमुख कायम रखने के लिए ही राष्ट्र शक्ति का प्रयोग करते हैं, किन्तु समय और परिस्थिति के अनुसार इस प्रभुत्व का स्वरूप विभिन्न प्रकार का हो सकता है। यथार्थवाद हम तथ्य से इंकार नहीं करता कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आते हैं। वास्तव में परिवर्तन तथा यथार्थवादी सिद्धान्त में कोई विरोधाभास नहीं है। राजनीतिक यथार्थवाद केवल इस बात पर जोर देता है कि परिवर्तन लाने

के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम राजनीति के मूढ़ तत्त्व को ही तिलांजलि दे दें। परिवर्तन राजनीतिक यथार्थ के ऊपर अमूर्त आदर्शों को बरीयता देकर नहीं लाया जा सकता। परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि सदा-जीवित शक्तियों (Perennial Forces) को चतुराई से सन्तुलित किया जाता रहे।

चौथा सिद्धान्त—राजनीतिक यथार्थवाद स्वीकार करता है कि राजनीतिक कार्यों का नैतिक महत्त्व भी है। वह इस बात से भी इंकार नहीं करता कि नैतिक आह्वान तथा राजनीतिक कार्यों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। पर साथ ही उसका विश्वास है कि सम्पूर्ण नैतिक सिद्धान्त अपने निगूढ़ स्पष्टीकरण में अथवा अमूर्त एवं सांबंधीय रूप में राज्य के कार्यों पर लागू नहीं किए जा सकते। उन्हें समय और स्थान की ठोस परिस्थितियों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए और परिस्थितियों के अनुकूल उनका प्रयत्न करना चाहिए। यथार्थवाद का प्राग्रह है कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धान्तों का पालन विवेक और सम्भावित परिणामों के आधार पर ही करना चाहिए। बिना विवेक के राजनीतिक नैतिकता कोई अर्थ नहीं रखती। एक व्यक्ति नैतिक सिद्धान्तों पर सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, लेकिन राज्य पर यह बात लागू नहीं होती। व्यक्ति कह सकता है कि “न्याय की विजय हो चाहे उसके पीछे दुनिया नष्ट हो जाए” किन्तु एक राज्य जिसमें नागरिक रहते हैं और जिनके समक्ष राष्ट्रीय अस्तित्व (National Survival) का नैतिक कर्त्तव्य उपस्थित है, ऐसा नहीं कह सकता। कोई भी राष्ट्र नैतिकता की दुहाई के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता।

पाँचवाँ सिद्धान्त—राजनीतिक यथार्थवाद किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सांबन्धिम नैतिक मूल्यों से पृथक् मानता है। किसी सांबन्धिम नैतिक कानून का पालन एक देश-विशेष के लिए आवश्यक रूप से लाभदायक ही हो, यह सत्य नहीं है। सम्भव है कि वह उसके लिए भयंकर परिणाम पैदा कर दे। नैतिक सिद्धान्तों की रक्षा के लिए अपने देश के हितों को बलिदान कर देने वाला व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिकता को तिलांजलि देना भी इतिहासकारों की निगाह में प्रशंसनीय नहीं है। ये दोनों ही अतिर्या (Extremes) हैं और इनसे बचने का उपयुक्त मार्ग यही है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित (शक्ति के रूप में परिभाषित) की दिशा में अग्रसर हो।

मॉर्गेन्थो ने यथार्थवाद के अपने पाँचवें सिद्धान्त के अन्तर्गत राजनीतिज्ञों और अध्येताओं को चेतावनी दी है कि वे राष्ट्रीय द्वारा दी जाने वाली नैतिकता की दुहाई से प्रभावित न हों। प्रत्येक राष्ट्र अपने कार्यों के समर्थन में नैतिकता की दुहाई अवश्य देता है, लेकिन वास्तव में वह केवल एक अभीष्ट की सिद्धि के लिए कार्य करता है और यह अभीष्ट है अपने हित की सुरक्षा। इतिहास सिद्ध करता है कि नैतिकता की दुहाई देते हुए धर्म के नाम पर कई राज्यों ने दूसरे राज्यों को नष्ट कर दिया। मध्यकालीन युग इस बात का प्रतीक है। दूसरे राष्ट्र की सहायता करने अथवा दूसरे

के विकास में मदद देने में भी एक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करता है। उदाहरणार्थ, अमेरिका यदि दूसरे राष्ट्रों को आर्थिक और नैतिक सहायता देता है तो ऐसा करने से वह अपने हितों की पूर्ति करता है अर्थात् साम्यवाद के प्रवाह को रोकता है। सन् 1975 के आरम्भ में अमेरिका ने पाकिस्तान को पुन. हथियार देने का निर्णय किया, क्योंकि उसके राष्ट्रीय हित की मांग है कि वह पाकिस्तान में सैनिक-सुविधाएँ प्राप्त करे या अरब राष्ट्रों से तेल के प्रश्न पर सहानुभूति प्राप्त करे। भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य बहुत कुछ यही है कि वह पड़ोसी राष्ट्र सुदृढ़ बन कर चीनी साम्यवाद के मार्ग में अवरोधक शक्ति बन जाए।

मॉर्गेंथो का कथन है कि यदि प्रत्येक राष्ट्र एक ही अभीष्ट सिद्धि (हित की सुरक्षा) के लिए उत्तुक है और यही उसके व्यवहार का मुख्य कारण है तो यह भी सम्भव है कि सभी राष्ट्र इस आधार पर सन्तुलित सम्बन्ध कायम कर लें और यदि ऐसा हो जाता है तो यह विश्व-शान्ति का एक प्रबल आधार बन जाएगा। राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक सूझ-बूझ के आधार पर सन्तुलन स्थापित कर लेना आज के युग की सबसे बड़ी नैतिकता होगी और यही वांछनीय भी है।

छठा सिद्धान्त—मॉर्गेंथो ने लिखा है कि उपर्युक्त सभी सिद्धान्तों के आधार पर यह स्पष्ट है कि राजनीतिक यथार्थवाद तथा अन्य दृष्टिकोणों में वास्तविक और गम्भीर अन्तर है। राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धान्त को चाहे कितना ही गलत समझा गया हो और उसे तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीतिक मामलों के प्रति इसके स्पष्ट बौद्धिक और नैतिक दृष्टिकोण का हम विरोध नहीं कर सकते।

यथार्थवाद के अपने इस छठे सिद्धान्त में मॉर्गेंथो ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतन्त्र विषय मानने की बात कही है। बौद्धिक रूप से राजनीतिक क्षेत्र उसी प्रकार से एक स्वतन्त्र क्षेत्र है जिस प्रकार अर्थशास्त्र अथवा समाजशास्त्र हैं। राजनीतिक यथार्थवाद मानव-प्रकृति के बहुत स्वरूप पर आधारित है। एक यथार्थवादी व्यक्ति आर्थिक मानव, राजनीतिक मानव, नैतिक मानव, धार्मिक मानव आदि का सम्मिलित स्वरूप है। किन्तु यदि हम इनमें से किसी एक स्वरूप का गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको अन्य स्वरूपों से अलग रखकर ही ऐसा कर सकते हैं। तभी यह अध्ययन सुव्यवस्थित ढंग से होगा। राजनीतिक अध्ययन में मानव-प्रकृति के अन्य स्वरूपों का स्थान प्रति गौण है और यही कारण है कि राजनीतिक यथार्थवाद में राजनीति की स्वतन्त्रता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। राजनीति के भी विभिन्न स्वरूप होते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति उनमें से एक है। अतः यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सुव्यवस्थित और गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे भी अन्य राजनीतिक प्रभावों जैसे आन्तरिक राजनीति आदि से यथासम्भव पृथक् रखना होगा। स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अपना स्वतन्त्र स्वरूप है।

राजनीतिक यथार्थवाद मानव-प्रकृति के बहुलवादी दृष्टिकोण पर किस तरह आधारित है और एक राजनीतिक यथार्थवादी किस प्रकार यह देखता है कि समुक्त नीति राष्ट्रीय शक्ति के हित में है भयवा नहीं—इसे माँगेंग्यो ने कतिपय उदाहरणों से प्रकट किया है ।

(क) सन् 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण किया । इस कार्य ने फ्रांस और इंग्लैंड के सामने दो विवादपूर्ण विषय उपस्थित कर दिए—एक कानूनी और दूसरा राजनीतिक । क्या इस कार्य से राष्ट्रसंघ के नियम को भंग किया है ? यदि किया है तो फ्रांस तथा ब्रिटेन को कौनसे प्रतिरोधी उपाय अपनाने चाहिए थे ? कानूनी रूप से कहा जा सकता था कि रूस ने जो कुछ किया वह राष्ट्रसंघ के नियमों के विरुद्ध था । राजनीतिक प्रश्न का उत्तर तीन बातों पर निर्भर था—फ्रांस और ब्रिटेन के हितों पर प्रभाव, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच विद्यमान शक्ति-विभाजन तथा दूसरी ओर सोवियत रूप और अन्य प्रबल शत्रु-राष्ट्रों (विशेषकर जर्मनी) के मध्य शक्ति-वितरण एवं इनका फ्रांस तथा ब्रिटेन के हितों और भावी शक्ति-विभाजन आदि पर प्रभाव । माँगेंग्यो का कहना है कि राष्ट्रसंघ के प्रमुख सदस्य होने के नाते फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस को संघ से निकलवा दिया और उनकी फिनलैंड को जाने वाली टुकड़ियों को स्वीडिश भू-भाग से मार्ग देने की स्वीडिश अस्वीकृति ने ही उन्हें रूस के विरुद्ध युद्ध में फिनलैंड का साथ देने से रोका । यदि स्वीडन की अस्वीकृति ने उन्हें बचाया न होता तो थोड़े ही समय में फ्रांस और ब्रिटेन को रूस और जर्मनी से एकसाथ युद्ध करना पड़ता । माँगेंग्यो के अनुसार फ्रांस और ब्रिटेन ने जो नीति अपनाई वह वैधानिकतावाद (Legalism) का एक सुन्दर उदाहरण थी । इन राष्ट्रों ने एक कानूनी प्रश्न को, जो अपने क्षेत्र में सर्व-सम्मत था, अपने राजनीतिक कार्यों द्वारा हल होने दिया । कानून और शक्ति दोनों ही प्रश्नों पर सका-समाधान करने के स्थान पर उन्होंने केवल कानून का प्रश्न ही पूछा और जो उत्तर उन्हें मिला वह उस विषय से तनिक भी सम्बन्धित नहीं था जिस पर उनका अस्तित्व निर्भर हो सकता था ।

(ख) दूसरा उदाहरण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'नैतिक-दृष्टिकोण' को स्पष्ट करता है । चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना ने पश्चिमी देशों को दो बातें सोचने के लिए विवश कर दिया—प्रथम, नैतिक और दूसरी, राजनीतिक । नैतिक दृष्टि से साम्यवादी सरकार को मान्यता दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न किया जाकर राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अनेक चीन को वास्तविक चीन माना गया और समुक्त राष्ट्रसंघ में सदस्यता प्रदान की गई । यह नीति अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल थी । राजनीतिक प्रश्न से सम्बद्ध हितों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में मदद दी कि चीन की साम्यवादी सरकार से बिल्कुल व्यवहार न रखना ही तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक विवेकपूर्ण था । पर चतुराई इस बात में थी कि राजनीतिक प्रश्न का नैतिक विषय के रूप में उत्तर प्रस्तुत किया गया अर्थात् इस बात पर विचार किया गया कि क्या साम्यवादी चीन की सरकार का स्वभाव और

नीतियाँ विश्व-शान्ति के नैतिक-अवश्यों (पाश्चात्य दृष्टिकोण से) के अनुरूप थीं। नैतिकता के नाम की आड़ में साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने योग्य नहीं पाया गया। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति 'नैतिकतापूर्ण दृष्टिकोण' का यह एक बौद्धिक खेल था।

मॉर्गेन्थो महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धान्त के जो उपरोक्त 6 नियम प्रतिपादित किए हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति का अध्ययन दो आधारों पर अपेक्षित है—(1) राजनीति जैसी कि वह वास्तव में है, (2) राजनीति जैसा कि उसे यथार्थवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए। यथार्थवादी सिद्धान्त का आधार ठोस तथ्य और इतिहास के अनुभव हैं, अतः विश्लेषण की यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसका पथ-प्रदर्शक विवेक है और इसलिए यह यथार्थ तथा भ्रमयार्थ में अन्तर करने में समर्थ है। मॉर्गेन्थो के अनुसार यही यथार्थवादी राजनीति का मुख्य तत्त्व है।

यथार्थवादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा
(Critical Evaluation of the Realistic Theory)

कोई भी सिद्धान्त सर्वथा पूर्ण और त्रुटिरहित होने का दावा नहीं कर सकता। मॉर्गेन्थो ने सम्भावित आलोचनाओं के प्रति सजग रहते हुए यथार्थवादी राजनीति के नियमों का निस्तृत विवरण दिया है और स्पष्टीकरण के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, तथापि उनके सिद्धान्त की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक विद्वानों द्वारा कटु आलोचना की गई है। रॉबर्ट टकर के अनुसार मॉर्गेन्थो के सिद्धान्त न तो वास्तविकता से मेल खाते हैं और न अपने आप में तो स्टेनले एच. हॉफमैन का कहना है कि इस सिद्धान्त में असंगतियों की भरमार है। हॉफमैन ने व्यवस्थित ढंग से मॉर्गेन्थो के सिद्धान्त और नियमों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है।¹

1. हॉफमैन मॉर्गेन्थो के शक्ति-सम्बन्धी विचारों से असहमत है। यदि हम शक्ति के यथार्थवादी विश्लेषण को एकदम सही मान लें तो यह विश्व एक ऐसा स्थिर रंगमंच प्रतीत होगा जिस पर चिरन्तन काल से केवल शक्ति-सम्बन्धों की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा है। शक्ति की इसी भूमिका के आधार पर मॉर्गेन्थो ने राजनीति को एक स्वतन्त्र विषय माना है और बहुत-कुछ इसीलिए उनका यथार्थवादी राजनीतिक विषय एकपक्षीय हो गया है। फिर, मॉर्गेन्थो यह भी स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि वे स्वायत्तता की बात किस आधार पर कर रहे हैं जबकि उनके यथार्थवाद का यह एक मुख्य तत्त्व है।

2. हॉफमैन का कहना है कि राजनीति को शक्ति का पर्यायवाची बना देना और शक्ति-सम्पर्क को ही राजनीति का 'सब कुछ' मान लेना उचित नहीं है। राजनीतिक मानव में आर्थिक मानव, धार्मिक मानव आदि भी सम्मिलित हैं, अतः

1 Stanley H. Hoffman (ed.) : Contemporary Theory in International Relations, pp. 30-38.

उमके केवल एकपक्षीय स्वरूप पर ही बल देने और उसे ही सम्पूर्ण राजनीति मान लेने का दृष्टिकोण भ्रामक है। यह स्थिति तो कुछ इस प्रकार की ही है जिसमें 'राजनीतिक मानव' को मानवता से गिराकर 'हैवान' बना दिया जाए। यह मानव का एक ऐसा विकृत स्वरूप होगा जिसे न तो यथार्थ ही कहा जा सकता है और न सत्य ही। 'शक्ति के प्रभुत्ववाद' (Power Monism) को सम्पूर्ण राजनीति का खोजक नहीं माना जा सकता और यह स्थिति तब और भी अधिक प्रशोभनीय हो जाती है जब हम माँगेंग्यो द्वारा परिभाषित शक्ति की व्याख्या को स्वीकार कर लेते हैं। शक्ति को बुराई के समकक्ष और राजनीति को सक्षम बना देना एक दोषपूर्ण और घातक विचार है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि राजनीति केवल बुराई है पर यह तो राजनीति का विकृत स्वरूप होगा, यथार्थ नहीं। राजनीति को केवल बुराई नहीं कहा जा सकता क्योंकि मानव-प्रकृति में निहित तत्त्व अन्धे और नुने दोनों होते हैं और इन्हीं तत्त्वों की अभिव्यक्ति राजनीति में भी होती है।

3 हॉफमैन के अनुसार यह स्वीकार करना भी अनुचित है कि सभी मानव-कार्यों के मूल में उसी प्रकृति सन्निहित है। हम परिस्थितियों के प्रभाव की अपेक्षा नहीं कर सकते। कई बार मनुष्य स्वभाववश नहीं बल्कि परिस्थितिवश बुराई कर बैठता है। इस प्रकार माँगेंग्यो का यथार्थवाद मानव-प्रकृति के सम्बन्ध में भी एक दोषपूर्ण तथा बहुत कुछ एकांगी विचार पर आधारित है।

4 हॉफमैन की दृष्टि में माँगेंग्यो ने शक्ति पर अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने शक्ति को राजनीतिक कार्यों का 'साध्य' बना दिया है जबकि वास्तव में शक्ति राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का 'साधन' मात्र है। शक्ति के स्वरूप, उसकी मात्रा आदि का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उद्देश्य क्या हैं? यदि माँगेंग्यो ने उद्देश्यों के अध्ययन पर समुचित बल दिया होता तो शक्ति को 'साध्य' बना देने की भूल न करते। यह एक खेदपूर्ण तथ्य है कि माँगेंग्यो ने उन सभी मान्यताओं की अवहेलना कर दी है जिनके आधार पर उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि आन्तरिक राजनीति इस दिशा में कम प्रभावशाली नहीं होती। इसी तरह सरकार के स्वरूप, नेतृत्व, शासकवर्ग की मान्यताओं आदि का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् में विदेश-नीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। माँगेंग्यो ने शक्ति के तत्त्व पर ही अत्यधिक बल दिया है और इस ज्वलन्त प्रश्न का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है कि अमुक राष्ट्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अमुक साधन क्यों अपनाता है। यह अपेक्षा माँगेंग्यो के राजनीतिक यथार्थवाद का एक गम्भीर दोष है।

5. अध्ययन-पद्धति (Methodology) के दृष्टिकोणों से भी केवल शक्ति के विचार पर ही बल देना अनुचित है। 'शक्ति' स्वयं विभिन्न तत्त्वों का सम्मिलित स्वरूप है। उदाहरणार्थ, शक्ति-नीति की शर्त का स्वरूप शक्ति-नीति का आधार, वर्तमान शक्ति तथा सम्भावित शक्ति आदि वे विभिन्न तत्त्व हैं जिनका शक्ति के

प्रयोग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शक्ति की इन विभिन्नताओं की उपेक्षा करके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र को भली प्रकार नहीं समझा जा सकता। मॉर्गेंथो का राजनीतिक यथार्थवाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र के एक शक्ति-आवृत्त विकृत स्वरूप को ही प्रस्तुत करता है और बहुत-कुछ यही कारण है कि मॉर्गेंथो ने 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है और इस तथ्य को भुला दिया है कि आधुनिक 20वीं शताब्दी के ससार में विभिन्नता और टकराव की जो स्थितियाँ मौजूद हैं वैसे पहले नहीं थी। राष्ट्रों की आन्तरिक राजनीतिक घटनाएँ भी उनकी विदेश-नीतियों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। विभिन्न और परस्पर विरोधी राजनीतिक गुट तथा दबाव-समूह निरन्तर सक्रिय रहकर विदेश-नीति के निर्णायकताओं को प्रभावित करते हैं। नीतियों को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ आज जितनी प्रबल हैं उतनी 18वीं और 19वीं शताब्दी में नहीं थी। उस समय राष्ट्रीय सरकारें आज जैसे राजनीतिक प्रभावों और दबावों से बहुत-कुछ मुक्त थी।

6. यथार्थवादी सिद्धान्त में अन्तर्निहित राष्ट्रहित सम्बन्धी विचार भी दोषपूर्ण है। मॉर्गेंथो ने राष्ट्रहित की सामान्य परिभाषा देते हुए यह समझ लिया है कि इस सम्बन्ध में विवाद जैसी कोई बात नहीं है। हॉफमैन का कहना है कि मॉर्गेंथो की राष्ट्रहित की कल्पना उस युग के लिए तो ठीक हो सकती थी जिसमें समाज एकरूपता लिए हुए हो, लेकिन आधुनिक समाज ऐसे नहीं है। वे विरोधों और अन्तर्विरोधों से परिपूर्ण हैं। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् में राष्ट्रहित पर कहीं भी मतभेद नहीं पाया जाता। आज का युग महान् प्राविधिक और वैज्ञानिक विकास का है जिसमें आए दिन भारी राजनीतिक उथल-पुथल होती रहती है। भौगोलिक स्थितियों, प्राकृतिक साधनों तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में हमारी पूर्व-मान्यताओं में आज काफी परिवर्तन आ गया है और प्राविधिक तथा वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ ये मान्यताएँ तेजी से बदलती जा रही हैं। इन परिवर्तित परिस्थितियों और मान्यताओं के प्रकाश में हम प्रकार का विचार सर्वथा दोषपूर्ण है कि राष्ट्रहित के बारे में कोई एक ही दृष्टिकोण अपनाया जाए।

7. यदि मॉर्गेंथो के सिद्धान्त को मान लिया जाए तो यह स्वीकार करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केवल एक ही पहलू है और वह है—विभिन्न राष्ट्रों के हितों में टक्कर। इस मान्यता को स्वीकार करने का रणनीतिक परिणाम यह होगा कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के विचार को सदैव के लिए तिलाञ्जलि देनी पड़ेगी।

8. मॉर्गेंथो की यथार्थवादी राजनीति का एक मुख्य तत्त्व 'विवेक' है। मॉर्गेंथो ने विदेश-नीति के विवेक-पक्ष पर अत्यधिक बल दिया है जबकि हॉफमैन का मत है कि जटिलताओं से परिपूर्ण आज के आन्तरिक युग में कुछ राष्ट्र ऐसी विदेश-नीतियों का अनुसरण करते हैं जो सर्वथा अविवेकपूर्ण लगती हैं, तथापि वे उनके अपने हित में होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का तानाबाना इतना पेचीदा और

दुर्बल हो रहा है कि कितनी ही बार राष्ट्र अपनी विदेश-नीति के संचालन में बाध्य होकर विवेक-पत्र को तिलान्त्रलि देकर ऐसे कदम तक उठा लेते हैं जो उनके लिए अहितकर होते हैं। उद्देश्यों के सम्बन्ध में भी मॉर्गेन्थो ने यथार्थ की बात की है लेकिन इस बात की कमा मारण्टी है कि यथार्थ 'विवेकपूर्ण' है।

9. मॉर्गेन्थो के यथार्थवादी सिद्धान्त का आधार मानव-प्रकृति है, किन्तु मानव-प्रकृति सम्बन्धी धारणा वैज्ञानिक न होकर बहुत कुछ अनुमान पर आधारित होती है। बेंनो वामरमैन¹ (Benno Wasserman) के अनुसार तो वे निम्नलिखित अप्रमार्गीय मारभूत नियमों (Unverifiable Essentialist Laws) पर आधारित हैं। वामरमैन ने अनुमानों के आधार पर सिद्धान्त-रचना करना वैज्ञानिक पद्धति नहीं कही जा सकती।

10. राजनीतिक यथार्थवाद में नैतिकता का तत्त्व भी आलोचना का पात्र है। मॉर्गेन्थो के अनुसार राष्ट्रहितों की पारम्परिक मान्यता के आधार पर विश्व के राष्ट्र मनुष्यवत् सम्बन्ध कायम कर सकते हैं और यही सर्वोच्च नैतिकता है, किन्तु इस प्रकार की मान्यता उसी मन्दन में उलटि हो सकती है जिसमें राष्ट्रहित विवादग्रस्त विषय न हों, पर आज के मधुरतल जटिल युग में राष्ट्रहितों की सर्वमान्यता की बात करना वास्तविकता में मुख मोड़ना है। पुनश्च राष्ट्रहित क्या है, यथार्थवादी सिद्धान्त इसकी कोई स्पष्ट और निश्चित व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता। राष्ट्रहित समय, परिस्थिति तथा राष्ट्रीय नीति के निर्धारण आदि के कारण मदेव एकमा नहीं रहता और यथार्थवादी सिद्धान्त भी राष्ट्रों के हितों को कोई निश्चित अर्थ प्रदान नहीं करता, तो फिर इस सिद्धान्त को राज्यों के आचरण के विनियम का सर्वोत्तम सिद्धान्त भी नहीं माना जा सकता।

11. रॉबर्ट टकर² और कनेथ वॉल्ज³ जैसे विद्वानों ने तो मॉर्गेन्थो के सिद्धान्त को यथार्थवादी ही नहीं माना है। उनका आरोप है कि मॉर्गेन्थो ने स्थान-स्थान पर वस्तुस्थिति का उल्लेख करने के साथ-साथ 'चाहिए' (Ought) जैसे आदर्शमूलक शब्द का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार मॉर्गेन्थो के विचार विगुह यथार्थवाद में दूर जाने दिखाई देने हैं और उन्हें मानव-प्रकृति एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रामाणिक तथा यथार्थवादी आधार नहीं माना जा सकता। मॉर्गेन्थो के विचारों में असंगतियाँ भी हैं। एक ओर तो उसने यथार्थवादी तथा आदर्शवादी तत्त्वों के बीच समन्वय का प्रयास किया है, दूसरी ओर नियतिवाद (Determinism) तथा पुनर्गर्भवाद जैसे विरोधी विचारों में तालमेल बँटाने का प्रयत्न किया है। विनियम में यह प्रकट होता है कि मॉर्गेन्थो का सिद्धान्त यथार्थवादी होने के साथ-साथ आदर्शवादी और मूल्य-परक (Value-Oriented) भी है। इसी प्रकार हम

1 Benno Wasserman : "The Scientific Pretensions of Professor Morgenthau's Theory of Power Politics," Australian Outlook (March 1959), p. 67.

2 Robert W. Tucker : Professor Morgenthau's Theory of Political Realism, American Political Science Review (March 1952), p. 214-24.

3 Kenneth N. Waltz : "Review Dilemmas of Politics"; American Political Science Review (June 1959), pp. 529-32.

देखते हैं कि राजनय द्वारा शक्ति-स्थापना के प्रसंग में माँगेंथो ने योग्य राजनीतिज्ञों की आवश्यकता पर बल दिया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 'शक्ति-संघर्ष' पर आधारित है और संघर्षों का समाधान राजनय द्वारा ही सम्भव है, तो इस प्रकार की कुचक्रपूर्ण स्थिति में बेचारे शान्तिवादी राजनयिक कैसे प्रवेश या सकेंगे और शान्ति-स्थापना का आदर्श कैसे प्राप्त कर सकेंगे। आलोचकों का आरोप है कि माँगेंथो ने वस्तुतः परस्पर विरोधी तत्त्वों और विचारों का सहारा लेकर अपने सिद्धान्त में विभिन्न सैद्धान्तिक जटिलताओं को पैदा कर दिया है।

सिद्धान्त का महत्त्व (Importance of the Theory)

माँगेंथो का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के लिए भारी वाद-विवाद का प्रश्न बना हुआ है। बैनो वासरमैन, हॉफमैन जैसे कटु आलोचकों ने इसकी पंक्तियाँ उड़ाई हैं, तो पॉम्पेयन तथा डेविड सिगर जैसे विद्वानों ने प्रशंसा के पुल बांधे हैं। हैरोल्ड स्प्राउट, क्विसी राइट जैसे विद्वानों ने माँगेंथो की देन को स्वीकार करते हुए भी उस पर अपूर्णता का दोषारोपण किया है। वास्तव में माँगेंथो आज के एक बहुचर्चित विद्वान् हैं जिनके सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया है, जिनके विचारों की आलोचना-प्रत्यालोचनाओं ने अनेक सैद्धान्तिक विवादों को जन्म दिया है और इन सबके परिणामस्वरूप उनका तथा उनके सिद्धान्तों का समुचित मूल्यांकन बड़ा कठिन हो गया है।

माँगेंथो के यथार्थवादी सिद्धान्त की आलोचनाएँ सबल हैं, किन्तु पूर्ण सत्य नहीं। हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में इस सिद्धान्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस सिद्धान्त ने राष्ट्रीय हितों और उनकी सिद्धि के लिए शक्ति के प्रयोग सम्बन्धी गम्भीर विचारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का पहली बार व्यापक विश्लेषण किया है और इस प्रकार इस विषय को सैद्धान्तिक आधार दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों के महत्त्व और उनके स्वरूप उत्पन्न होने वाले संघर्षों आदि तथ्यों को हम ठुकरा नहीं सकते। हम इस कटु सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि आज का युग बहुत बड़ी सीमा तक 'शक्ति-संघर्ष' का युग है जिसमें राजनीति के सभी दांव-पेचों का प्रयोग किया जाता है और राष्ट्र अपने हित को ध्यान में रखकर ही विदेश-नीति का संचालन करता है। हम चीन को लें या पाकिस्तान को, रूस को लें या अमेरिका को, उगाण्डा को लें या रोडेसिया को, श्रीलंका को लें या बर्मा को—सभी राष्ट्र समयानुसार नैतिक-अनैतिक कारणों और नीतियों की परवाह न करते हुए राष्ट्रीय हित के सर्वार्थ में ही लगे रहते हैं और अपनी सामर्थ्य तथा साधन-सम्पन्नता के अनुरूप 'शक्ति-संघर्ष' भ्रमवा 'शक्ति-राजनीति' का खेल खेलते हैं। इस खेल को खेलने के स्वरूप में अन्तर हो सकता है, लेकिन खेल की प्रवृत्ति आधारभूत रूप में वही है।

प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थ की पूर्ति में सलग्न है। उसका स्वार्थ यह है कि वह अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करे। इस बात पर जोर देकर यथार्थवादी विचारधारा दो प्रमुख सन्देश देती है, जिनको अपनी विदेश-नीति निर्धारित करते समय प्रत्येक

राष्ट्र को ध्यान में रखना चाहिए। पहला सन्देश यह है कि विदेश-नीति ऐसी बनाई जाए जो शक्ति बढ़ाने एवं बनाए रखने में हमारे राष्ट्र की अधिक से अधिक सहायता कर सके। दूसरा सन्देश, जो इसी से सम्बन्धित है, यह है कि हम अपनी विदेश-नीति का निर्माण करते समय यह भी ध्यान रखें कि दूसरे देश का राष्ट्रीय हित क्या है तथा वह हमारे हित से (जहाँ तक सम्भव हो सके) टकराए नहीं।

इसके अतिरिक्त चूँकि यथार्थवादी सिद्धान्त का आधार बुद्धि है, अतः इससे प्रभावित विदेश-नीति भी बुद्धि तथा तर्क पर आधारित होगी। ऐसी विदेश-नीति में खतरा (Risk) लेने का स्थान कम रहता है तथा अधिकांश बातें एक योजना के अनुसार घटती चली जाती हैं। इस प्रकार की विदेश-नीति राजनीतिक रूप से सफल होती है तथा नैतिक रूप से भी इसकी प्रशंसा की जाती है। यह विदेश-नीति का एक बड़ा गुण माना जाता है कि वह यथार्थवादी हो।

विगत कुछ वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को वैज्ञानिक आधार पर अधिकाधिक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया गया है और अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे रिचर्ड स्टाइडर का नीति-निर्धारण सम्बन्धी दृष्टिकोण, काप्लान का व्यवस्था-विश्लेषण, चार्ल्स मँक्लेलेण्ड का सामान्य व्यवस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण, जॉर्ज लिस्का का साम्बावस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण, आदि। ये विभिन्न प्रयास इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र माँगेंवो के सिद्धान्त से आगे बढ़ चुका है। व्यवस्था-दृष्टिकोण (System Approach) को आज यथार्थवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है, लेकिन यह सारी प्रगति भी माँगेंवो के सिद्धान्त के महत्त्व की उपेक्षा नहीं करती। व्यवस्था-दृष्टिकोण के विकास का आंशिक श्रेय भी माँगेंवो को ही है, क्योंकि यह उन्हीं के द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अध्ययन तथा शोध का परिणाम है। माँगेंवो ने इस विषय को आदर्शवाद से हटा कर व्यवस्थापरक दृष्टिकोण तक लाने में महती भूमिका निभाई है। माँगेंवो की देन इस रूप में भी कम नहीं है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर दूसरे विचारकों को भी इस दिशा में कार्य करने को प्रेरित किया। कॅनेथ वाल्ड्ज ने लिखा है कि माँगेंवो ने किसी सिद्धान्त को प्रतिपादित करने की अपेक्षा उसके निर्माण के लिए सामग्री प्रस्तुत की है।¹ इसी प्रकार कॅनेथ थॉम्पसन का निवार है कि माँगेंवो का सिद्धान्त अभी विकास की स्थिति में है और उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होना अभी शेष है।² इन सभी आलोचनाओं-प्रत्यालोचनाओं के परिणाम में यह निष्कर्ष असन्दिग्ध है कि माँगेंवो के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के द्वाे सिद्धान्तों को चुनौती नहीं दी जा सकती और उनके यथार्थवादी सिद्धान्त को समय ने पूरी तरह असत्य सिद्ध नहीं किया है। हम उनके सिद्धान्त की उपादेयता को अस्वीकार नहीं कर सकते।

1 *Kenneth W. Waltz : Review Dilemmas of Politics*, pp. 529-30.

2 *Kenneth W. Thompson : Christian Ethics and the Dilemmas of Foreign Policy*, p. 133.

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-विज्ञान : पुराने और नए विकासों का सर्वेक्षण

(Science of International Politics : A Survey
of Old and New Developments)

“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्य निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं, विश्व की घटनाएँ भारचर्यजनक ढंग से घटित होती रहती हैं। जो व्यक्ति उनमें अपने भूतकालीन ज्ञान अथवा वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य का अनुमान करना चाहता है, उसके लिए विश्व की समस्याओं के भण्डार में सदा आश्चर्यान्वित करने वाले तथ्य विद्यमान रहते हैं।” —मॉर्गेंथो

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिकता विद्वानों में पर्याप्त विवाद का विषय है। कुछ विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान है तो कुछ इस मत के विरुद्ध हैं। किसी राइट जैसे विद्वानों का विश्वास है कि यह निकट भविष्य में विज्ञान बन सकेगा जबकि स्टेनले हॉफमैन को सन्देह है कि यह कभी भी विज्ञान बन पाएगा।

विख्यात राजनीति-शास्त्री हंस जे मॉर्गेंथो ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ‘राष्ट्रों के मध्य राजनीति’ (Politics Among Nations) में ‘अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-विज्ञान’ पर एक पृथक् अध्याय लिखा है और इस सम्बन्ध में बड़े तार्किक ढंग से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हम पहले मॉर्गेंथो के दृष्टिकोण¹ को विस्तार से प्रकट करेंगे और बाद में कुछ वर्षों में उठे ‘विज्ञान तथा परम्परावाद’ (Science V/s Traditionalism) सम्बन्धी उस गम्भीर विवाद की विवेचना करेंगे जिसे मॉर्टन काप्लान ने ‘नवीन महान् बहस’ (The New Great Debate) की सजा दी है।

मॉर्गेंथो के विचार (Morgenthau's Views)

मॉर्गेंथो के अनुसार प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की भांति अन्तर्राष्ट्रीय

राजनीति की वैज्ञानिकता के सम्बन्ध में भी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। प्रत्येक वैज्ञानिक ज्ञान का स्वाभाविक लक्ष्य उन शक्तियों की खोज है जो किसी सामाजिक घटना के पीछे व्याप्त हैं और साथ ही यह भी देखना होता है कि वे शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रसंग में भी इस लक्ष्य पर जोर देना युक्तिरंगत है। उन शक्तियों को जानना और समझना चाहिए जो राष्ट्रीय के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित करती हैं और साथ ही उन तरीकों को भी समझना चाहिए जिनके द्वारा ये शक्तियाँ एक-दूसरे पर और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्धों तथा संस्थाओं पर प्रकाश डालती हैं।

विभिन्न दृष्टिकोण (Different Approaches)

उपयुक्त प्रसंग में कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। डॉ. फ्रेसन कर्क ने समुक्तराज्य अमेरिका में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन के सन्दर्भ में तीन दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है—

प्रथम दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। इतिहासकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को केवल आधुनिक इतिहास समझते हैं जिसमें अधिकृत सामग्री पर्याप्त मात्रा में न होने से विद्यार्थी को कठिनाइयाँ होती हैं।

द्वितीय दृष्टिकोण वैधानिक है। अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं ने अपने आपकी राज्यों के आपसी सम्बन्धों के कानूनी पक्ष के अध्ययन में सलग्न रखा है, पर उन्होंने इस बात का कभी भी गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न नहीं किया कि वे कौन-से आधारभूत कारण हैं जिनसे यह वैधिक (Legal) परिधि सदा ही अपूर्ण और अधूरी रहती चली आई है।

तृतीय दृष्टिकोण के समर्थकों में वे लोग हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के पथार्थ रूप में अधिक रुचि नहीं रखते, केवल उस आदर्श रूप में अधिक रुचि रखते हैं जो अपने आप में पूर्ण हो और जिसे वे स्वयं निमित्त करना चाहते हैं।

डॉ. फ्रेसन कर्क ने आगे लिखा है कि काली समय बाद केवल आधुनिक काल में ही ऐसे विद्यार्थी आगे आए हैं जिन्होंने विश्व-राजनीति की आधारभूत एवं शाश्वत शक्तियों का अध्ययन प्रारम्भ किया है तथा उन संस्थाओं का अध्ययन भी शुरू किया है जो इन शक्तियों को अपने में समेटे हुए हैं। यह अध्ययन इस इच्छा से प्रेरित है कि उन आधारभूत हलचलों को समझा जाए जो किसी राज्य की विदेश-नीति का निर्माण करती हैं। डॉ. कर्क का निष्कर्ष है कि “इस प्रकार अन्त में राजनीतिक वैज्ञानिक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गंदायण कर ही रहा है।”

डॉ. कर्क की विषय-वस्तु के आधार पर ही प्रो. चार्ल्स ई. मार्टिन ने लिखा है—“अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के शिक्षकों और छात्रों के सामने सर्वाधिक ज्वलन्त समस्या द्वैतवाद (Dualism) है जिसका हमें दो भिन्न और विरोधी क्षेत्रों में सामना करना पड़ता है। मेरा तात्पर्य एक ओर शान्ति-संस्थाओं के क्षेत्र (The Area of Institutions of Peace) से है जो आपसी झगड़ों को सुलझाने से सम्बन्धित हैं

और दूसरी ओर शक्ति-राजनीति तथा युद्ध के क्षेत्र (The Area of Power Politics and War) से है। ऐसा होना सर्वथा अपेक्षित है। इससे कोई बचाव नहीं है। मेरा विचार है कि हमारे अध्ययन-अध्यापन के दृष्टिकोण का पिछले 20 वर्षों में एक सबसे बड़ा दोष शायद यह रहा है कि हमने युद्ध-पद्धति और शक्ति-राजनीति के अभाव से सम्बन्धित पुस्तकों के प्रभाव को अनदेखा ही कर दिया है। मेरा विचार है कि ऐसा करने में राजनीतिक-वैज्ञानिक बड़ी भूल कर रहे हैं। हमको शक्ति-राजनीति और उसके परिणामों तथा उससे उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए और हमें युद्ध-पद्धति के अध्ययन से भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए।”

हंस मॉर्गेंथो का कथन है कि यदि उपर्युक्त व्याख्या को स्वीकार किया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक अध्ययन-विषय के रूप में आधुनिक इतिहास और वर्तमान घटनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राजनीतिक सुधारों से भिन्न होगी। मॉर्गेंथो का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आधुनिक इतिहास और वर्तमान अथवा प्रचलित घटनाओं के अनिरिक्त और भी अन्य तथ्यों का समावेश होता है। पर्यवेक्षक वर्तमान स्थिति और उसके निरन्तर बदलते हुए दृष्टिकोणों से घिरा हुआ है। उसे खड़े होने के लिए कोई ठोस भूमि प्राप्त नहीं है और न ही उसके पास मूल्यांकन के कोई वस्तुपरक मापदण्ड है। इस आधारभूमि और मापदण्ड की प्राप्ति उन आधारभूत तत्वों तक पहुँचे बिना नहीं हो सकती जो तभी स्पष्ट हो सकते हैं जब आधुनिक घटनाओं को सुदूर अतीत से जोड़ा जाए और दोनों को मानव-स्वभाव की शाश्वत प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में देखा जाए।

हंस मॉर्गेंथो के अनुसार हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को वैधिक नियमों अथवा सस्याओं पर ही सीमित नहीं कर सकते। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इन नियमों के ढाँचे में तथा इन सस्याओं द्वारा कार्यशील होती है, किन्तु उनके समान ठीक यह उसी प्रकार साम्य नहीं रखती जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राजनीति वहाँ के संविधान, संघीय कानूनों और संघीय सरकार के अभिकरणों से रखती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में क्या है और किस लिए है—इन बातों को समझे बिना इसको सुधारने के प्रयत्नों के बारे में हम विलियम ग्राहम समनेर के निम्नलिखित दृष्टिकोण से सहमत हो सकते हैं—

“परिस्थितियों और मानव-प्रकृति के यथार्थ स्वरूप की ठीक-ठीक परीक्षा करने के स्थान पर केवल कुछ महान् आदर्शों और मान्यताओं को पूर्वाग्रह के रूप में मानकर चलना राजनीतिक वाद-विवाद का सबसे बड़ा दोष है। कतिपय उच्च और अधिक श्रेष्ठ वस्तुओं का एक आदर्श पहले से ही बना लिया जाता है जो यथार्थतः वर्तमान परिस्थिति से कहीं ऊँचा होता है और प्रायः अनजाने ही आदर्श वा अस्तित्व वर्तमान स्थिति में मान लिया जाता है। उसे पुनः ऐसे चिन्तन का मानदण्ड मान लिया जाता है जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। राजनीतिक विषयों पर मूढ़म अथवा अमूर्त चिन्तन का तरीका ही वास्तव में गलत है। इस तरीके को लोकप्रियता इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह सरल है। इस जगत को जानने की अपेक्षा

एक नए जगत की कल्पना करना आसान होता है। राज्यों के इतिहास और संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा कुछ लोकप्रिय स्वीकृत तथ्यों के आधार पर चिन्तन की उड़ान अधिक आसान है। इस अध्ययन की अपेक्षा कि वे सही हैं अथवा नहीं, लोकप्रिय तारे भी आसान होते हैं। ये सब बातें शकाओं और गड़बड़ी को प्रोत्साहन देती हैं, कोरे उपदेशों और लोकोक्तियों को बढ़ावा देनी हैं तथा विवादों अथवा संघर्षों को बढ़ानी हैं, किन्तु राष्ट्रों की समृद्धि में इनसे कोई लाभ नहीं होता।”
समझ की सीमाएँ (Limitations to Understanding)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा सम्बन्धों का वैज्ञानिक अध्ययन एकदम मुश्किल नहीं है। सैद्धान्तिक खोज में निरीक्षणकर्ता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विवसी राइट, हंस मॉर्गेंथो, आदि विद्वानों ने इन कठिनाइयों अथवा सीमाओं का रूप में स्पष्टीकरण बड़े तर्कसम्मत किया है—

1. अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ परिवर्तनशील हैं। मानवीय क्रियाएँ होने के कारण इनके बारे में यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि यदि कुछ विशेष परिस्थितियाँ उपस्थिति हो जाएँ तो फिर उनका क्या परिणाम होगा और एक देश-विशेष की नीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य अथवा सरकारों के व्यवहार को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीका अभी अपनाया जा सकता है जब हम यह मानकर चलें कि ये मनुष्यों और उनके दृष्टिकोणों का उपयोग है अथवा एक विश्व-व्यवस्था का भाग है।¹

2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मानवीय क्रियाएँ हैं और यह अस्वाभाविक नहीं है कि वैज्ञानिक निष्कर्ष निष्पक्ष या सत्य न रह सकें। जब किसी जड़ वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है तो अध्येता निष्पक्ष रहते हुए भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन मानव-सम्बन्धों के अध्ययन के बारे में यह सदेहास्पद है। किसी का यह सामान्यीकरण हास्यास्पद ही होगा कि “एक पाकिस्तानी सैनिक तीन भारतीय सैनिकों के बराबर होता है” और यदि इस सामान्यीकरण को सच भी मान लिया जाए तो इससे भारतीय जवानों में प्रतिक्रिया होगी, उनका साहस बढ़ जाएगा। सन् 1965 और बाद में सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध इस तथ्य को अच्छी तरह दोहरा चुके हैं।

3. तीसरी बड़ी कठिनाई तथ्यों की दुर्लभता और अस्पष्टता सम्बन्धी है। पर्यवेक्षक जिन घटनाओं को जानने का प्रयत्न करता है वे स्वयं विलक्षण होती हैं। ये घटनाएँ एक विशेष प्रकार से एक ही बार घटित होती हैं और उस रूप में न तो पहले घटी थी और न भविष्य में घटेंगी। इसके अतिरिक्त ये घटनाएँ मिलती-जुलती भी होती हैं क्योंकि वे सामाजिक शक्तियों का स्पष्टीकरण हैं। सामाजिक शक्तियाँ मानव-स्वभाव का गतिशील रूप हैं, अतः जब एक ही परिस्थिति के अन्तर्गत सामाजिक शक्तियाँ समान रूप में प्रकट होती हैं तो यह समस्या उत्पन्न हो जाती है

कि समान घटनाओं और विलक्षण घटनाओं के बीच रेखा कहाँ खींची जाए। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति ऐसी है कि इनमें एकदम सुनिश्चित वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं हो सकता और न ही ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जैसे भौतिक शास्त्रों में। मॉर्गेंथो के शब्दों में, “जो पहला पाठ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को सीखना है और जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जटिलता सामान्य समाधान तथा विश्वसनीय भविष्यवाणी को असम्भव बना देती है।” आगे मॉर्गेंथो लिखते हैं कि “इसीलिए सबसे धोपठ काम जो एक विद्वान् विद्यार्थी कर सकता है वह यह है कि किसी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की विभिन्न प्रवृत्तियों की खोज करे जो उसमें सम्भावनाओं के रूप में निहित रहती हैं। वह उन विशेष परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है जिनके फलस्वरूप एक तरह की प्रवृत्ति के व्यापक हो जाने की अधिक सम्भावना है और इस प्रकार वह अनुमान लगा सकता है कि वास्तव में भिन्न परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ प्रकट होकर किस प्रकार प्रभावकारी होंगी।” मॉर्गेंथो का विचार है कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्य निरन्तर बदलते रहते हैं, विश्व की घटनाएँ आश्चर्यपूर्ण ढंग से घटती रहती हैं और जो व्यक्ति उनमें अपने भूतकालीन ज्ञान तथा वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाना चाहता है उसके लिए विश्व की समस्याओं के भण्डार में सदैव आश्चर्यचकित करने वाले तथ्यों की कमी नहीं है।” जब बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों की भविष्यवाणियाँ बुरी तरह असफल सिद्ध हो जाती हैं तो सामान्य विद्यार्थियों अथवा अध्येताओं के छोटे मस्तिष्कों की भविष्यवाणी से क्या आशा की जा सकती है? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हम उन लोगों पर क्या विश्वास कर सकते हैं जो दृढ़तापूर्वक बतलाते हैं कि “कल व परसों क्या होने वाला है?”

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिकता के सम्बन्ध में विवसी राइट का मत कुछ उदार है। उनका विचार है कि यद्यपि अनेक कठिनाइयों के फलस्वरूप हम इस विषय को पूरी तरह विज्ञान का रूप नहीं दे सकते तथापि यह मानना भ्रामक होगा कि वैज्ञानिक विधियों (निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, सारणीकरण का प्रयोग, निष्कर्ष, आदि) का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में किसी भी स्तर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। विज्ञान की अनेक विशेषताएँ जैसे वस्तुपरकता (Objectivity), निश्चिन्ता (Accuracy), मात्रानुकरण (Quantification), तर्क (Logic) आदि का प्रयोग नागरिकों, नेताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोणों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। आधुनिक युग में सभी व्यवस्थाओं को आवश्यक रूप से विज्ञान बन जाना है, चाहे उनके विज्ञान बनने के मार्ग में कितनी ही बाधाएँ क्यों न आएं।¹ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी समय की माँग के अनुसार विज्ञान बनना ही होगा। इनका प्रारम्भ

1 *Hedley Bull : International Theory—The Case for a Classical Approach, World Politics (April 1966), pp. 361-77.*

कला या इतिहास के रूप में हुआ, तत्पश्चात् दर्शन की भाँति सामान्यीकरण हुआ और अब समय है कि इनको वैज्ञानिक रूप दिया जाए।

**अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विशिष्ट समस्याओं पर
विलियम डी. कॉपलिन का विश्लेषण¹
(William D. Coplin's Analysis of the Problems
Specific to International Politics)**

विलियम डी. कॉपलिन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिकता से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं पर अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वे विषय-वस्तु की और अधिक घबड़ी तरह समझने में उपयोगी होंगे। कॉपलिन ने सर्वप्रथम ज्ञान-प्राप्ति की दिशा में वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method as an Approach to Knowledge) को स्पष्ट किया है और तत्पश्चात् वैज्ञानिक पद्धति के बिन्दुओं को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के सन्दर्भ में लागू करके बतलाया है कि वैज्ञानिकता की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विशिष्ट समस्याएँ क्या हैं। कॉपलिन ने स्पष्ट किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अन्वेषणात्मक और सिद्धान्तों (Concepts and Theories) के विकास के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं और इसी प्रकार सिद्धान्तों के परीक्षण सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी विद्यमान हैं। ये कठिनाइयाँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनने से रोकती हैं, लेकिन उनके आधार पर हम उसे एक विकसमञ्जल सामाजिक विज्ञान के पद से नहीं हटा सकते। ज्ञान-प्राप्ति की दिशा में वैज्ञानिक दृष्टि

(Scientific Method as an Approach to Knowledge)

किसी भी ज्ञान (Knowledge) के समुचित उत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method) का विशेष महत्त्व है। विज्ञान की कार्यविधियों या प्रक्रियाओं का एक पुञ्ज (A Set of Procedures) कहा जा सकता है जिसके आधार पर हम किसी विषय के बारे में ज्ञान की संरचना करते हैं और इस तरह न केवल पूर्वापेक्षा अधिक ज्ञानवान बन पाते हैं बल्कि भविष्यवाणियाँ करने अथवा भावी घटनाओं का संकेत देने और मानकीय या नियामक निर्णय (Normative Judgements) देने में समर्थ होते हैं।² विज्ञान का लक्ष्य एक सहभागी ज्ञान की रचना के लिए (For Building Shared Knowledge) एक आधार प्रदान करना है।³ सहभागी ज्ञान (Shared Knowledge) के आधार-निर्माण में यह विचार अन्तर्निहित है कि एक वैज्ञानिक के निष्कर्ष और अध्ययन इस प्रकार के होने चाहिए जिन्हें दूसरे वैज्ञानिक उसी प्रकार समझ सकें जिस प्रकार कि उस मूल वैज्ञानिक

1 William D. Coplin : *Introduction to International Politics—A Theoretical Overview*, 1974, pp. 7-22.

2 "Science is a set of procedures for building knowledge about what exists so that men not only are more knowledgeable but also are better able to predict, make normative judgements, and prescribe."

—William D. Coplin : *op. cit.*, p. 7.

3 "The goal of science is to provide a basis for building shared knowledge."

—*Ibid.*, p. 7.

(The Original Scientist) ने समझाना चाहा था। ज्ञान (Knowledge) का अभिप्राय इस बात से है कि एक व्यक्ति अपने विचारों के सहीपन (Accuracy) का मूल्यांकन कैसे करता है। जो कथन प्रामाणिक समझे जाते हैं उन्हें ज्ञान कहा जा सकता है।

वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में सामान्य भाषा (A Common Language) के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि विज्ञान की किसी भी शाखा की प्रभावशीलता की कुँजी यह है कि कुछ ऐसी विशिष्ट भाषा (Specialized Language) हो जिसके माध्यम से विषय-विशेष के विचारों का आदान-प्रदान हो सके। प्रत्येक विज्ञान का इतिहास यह बताएगा कि उसकी एक अपनी विशेष भाषा का विकास हुआ है जिसमें न केवल संक्षेप में परिभाषित शब्दावलियाँ (Precisely Defined Terms) उपलब्ध होती हैं बल्कि विशेष दशाओं या अवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए प्रमापों की व्यवस्थाएँ (Systems of Measurements to Define Conditions) भी होती हैं। वास्तव में एक सामान्य भाषा के विकास को अंशतः सहभागी अवधारणाओं के विकास की प्रक्रिया के रूप में (As a Process of Evolving Shared Concepts) लिया जा सकता है। एक अवधारणा (A Concept) को हम एक शब्द या कुछ शब्दों का समूह मान सकते हैं जिसका प्रयोग किसी चीज को संक्षेप में बताने के लिए किया जाता है ताकि दूसरे लोग (जो समाजशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आदि क्षेत्र से सम्बन्धित हों) उसे सुगमता से समझ सकें। जो विद्वानों को एक-दूसरे को समझने और अध्ययन-विषय की व्याख्या में सहायता करने में जितने समर्थ होते हैं वे उतने ही अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि एक क्षेत्र-विशेष के सभी विद्यार्थी सम्प्रत्ययों (Concepts) की एक-सी व्याख्याएँ देंगे। इस क्षमता की एक कसौटी यह है कि सम्प्रत्ययों को व्यावहारिक परिभाषाओं के माध्यम से परिवर्तनीय तत्वों या चलो में रूपान्तरित किया जा सकता है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में परिभाषाएँ संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए ताकि उन परिभाषाओं को प्रयोग में लाने वाले विभिन्न विद्वान् एक ही घटना के बारे में समान आँकड़ों या सामग्री को एकत्र कर सकें। कोई भी चल (Variable) तभी विश्वसनीय माना जाता है जबकि परिभाषा संक्षिप्त और स्पष्ट हो तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा लगभग समान सामग्री या सूचना उत्पन्न करने में सक्षम हो। यद्यपि सभी सम्प्रत्ययों को सफलतापूर्वक चलों में रूपान्तरित नहीं किया जा सकता, तथापि इस प्रकार की सम्भावनाओं का क्षेत्र अधिकाधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। चलों के विकास की विधि का विशेष महत्व है, क्योंकि जो विधि जितनी कुशल होगी, विभिन्न सम्प्रत्ययों की व्याख्या में त्रुटियाँ रहित होने की उतनी ही कम सम्भावना रहेगी।

सहभागी भाषा को आगे लाने में सम्प्रत्ययों का विकास महत्वपूर्ण है और इस बात से ही सम्बन्धित दूसरी बात सम्प्रत्ययों का आपसी सम्बन्ध है। प्रायः किसी एक कथन के लिए विभिन्न शब्दावलियाँ दी जाती हैं, जिनमें दो अथवा अधिक सम्प्रत्यय एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। जब कोई कथन किसी अपरीक्षित विचार

का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे साधारणतया प्रस्थापना (Proposition) कहा जाता है। यदि इस प्रस्थापना को परीक्षण योग्य रूप में (In a Testable Form) प्रस्तुत किया जाता तो उसे उपकल्पना (Hypothesis) कहते हैं। उन प्रस्थापनाओं और/अथवा एक-दूसरे से सम्बन्धित उपकल्पनाओं के पुञ्जों को सिद्धान्त (Theory) कहते हैं। विज्ञान वास्तव में वही है जो वैज्ञानिक या अध्ययनकर्त्ता को अपने सिद्धान्तों में विश्वास के निर्माण के लिए पद्धतियाँ प्रदान करे।

किसी भी ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में वैज्ञानिक पद्धति की इस पृष्ठभूमि के उपरान्त अब हम अपने मूल विषय पर आ सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करने में अर्थात् सम्प्रत्ययो और सिद्धान्तों के विकास में तथा प्रस्थापनाओं और सिद्धान्तों को जाँचने में क्या कठिनाइयाँ हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को विशिष्ट समस्याएँ
(Problems Specific to International Politics)

विलियम डॉ. कापलिन (William D. Coplin) ने वैज्ञानिक पद्धति सम्बन्धी उपर्युक्त सामान्य बिन्दुओं को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में ज्ञान-प्राप्ति की दिशा में लागू किया है और अपने विवेचन को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है—

- (1) सम्प्रत्ययो और सिद्धान्तों के विकास में कठिनाइयाँ, तथा
- (2) सिद्धान्तों और उल्लेख्य प्रस्थापनाओं के जाँचने में कठिनाइयाँ।

इनमें प्रथम विवेचना का सम्बन्ध ज्ञान की सहभागिता (The Sharing of the Knowledge) से है और दूसरी का सम्बन्ध सिद्धान्तों की प्रामाणिकता (The Validity of the Theories) से है।

(1) सम्प्रत्ययों और सिद्धान्तों के विकास में कठिनाइयाँ (Difficulties in Developing Concepts and Theories)—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सम्प्रत्ययों और सिद्धान्तों के विकास के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं—

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों और राजनीतिक कर्त्ताओं (The Political Actor) के बीच जो उन्मुक्त और तीव्र अन्त क्रियाएँ होती हैं उनके कतस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्प्रत्ययो और सिद्धान्तों के प्रयोग में संक्षिप्तता और स्पष्टता का अभाव बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों द्वारा सम्प्रमुना, राष्ट्रीय-हित और शक्ति जैसे सम्प्रत्ययों का और इसी तरह शक्ति-सन्तुलन अथवा राज्यों के व्यवहार पर भूगोल का प्रभाव जैसे सिद्धान्तों का विकास किया गया है और इन सम्प्रत्ययों तथा सिद्धान्तों के माध्यम से उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करने की चेष्टा की है, लेकिन राजनीतिज्ञों और विदेश-नीति निर्माताओं ने भी अपने भाषणों और विचारों में इन सम्प्रत्ययों और सिद्धान्तों का प्रयोग किया है। दोनों ही पक्षों की इस सहभागिता का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्प्रत्ययो और सिद्धान्तों के विकास में संक्षिप्तता और स्पष्टता का अभाव रहा है। राजनीतिक

नेताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्प्रत्ययों और सिद्धान्तों का प्रयोग अपने राज्यों की नीतियों का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया है और फलस्वरूप इन सम्प्रत्ययों और सिद्धान्तों के अनेक अर्थ निकल आए हैं तथा एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उनके बारे में कोई मतभेद नहीं पाया जाता, कोई ऐसा सहभागी ज्ञान (A Shared Knowledge) विकसित नहीं हो पाता जिस पर विद्वान् और राजनीतिक नेता दोनों एकमत हो या एक से विचार रखते हो।

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र इतना विशाल और जटिल है कि सम्प्रत्ययों और सिद्धान्तों के विकास में दो परस्पर विरोधी किन्तु निरोधक प्रवृत्तियाँ (Inhabiting Tendencies) उत्पन्न हो गई हैं—

(i) कुछ विद्वान् पूरी तरह किन्हीं विशिष्ट नीतियों अथवा घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं और सामान्य निष्कर्षों के विकास की समुचित चिन्ता नहीं करते।

(ii) ऐसे भी विद्वान् हैं जो अभूत व्याख्याओं के विकास पर अत्यधिक बल देते हैं और इस बात की उपेक्षा कर देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति बहुकारणात्मक (Multicausal) है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र की जटिलता परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करती है जो सम्प्रत्ययों और सिद्धान्तों के विकास के विपरीत होती हैं। एकदम कठोर रुख अपनाने और सामान्यीकरण की आवश्यकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि वह प्रवृत्ति कि किन्हीं विशिष्ट सम्प्रत्ययों और सिद्धान्तों से सगति बँधाने के लिए अत्यधिक सरलीकृत व्याख्याओं का विकास किया जाए। वास्तव में उन सम्प्रत्ययों और सिद्धान्तों में, जिनको बड़ी संकीर्णता से परिभाषित और प्रयुक्त किया है और उनमें जिनको बहुत विस्तृत रूप से परिभाषित और लागू किया जाता है, एक सन्तुलन आवश्यक है, हालाँकि विषय-वस्तु की जटिलता विद्वानों को किसी अति (Extremes) की ओर धकेलती है।

(2) सिद्धान्तों और प्राप्त प्रस्थापनाओं को जाँचने में कठिनाइयाँ (Difficulties in Testing Theories and Derived Propositions)—

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता सिद्धान्तों को जाँचने में भी कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। जिन सिद्धान्तों में बड़ी संख्या में अन्तःक्रिया करने वाले चल (Interacting Variables) निहित होते हैं, उन्हें सुगमतापूर्वक परीक्षणयोग्य प्रस्थापनाओं तक नहीं लाया जा सकता। अल्पपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुकारणात्मक सिद्धान्तों का निर्माण करने को विवश हो जाता है, अतः अपने विचारों के सहीपन की उसकी औपचारिक जाँच प्रायः सीमित होती है। उदाहरणार्थ, यदि हमने यह सिद्धान्त विकसित किया है कि विदेश-नीति-व्यवहार (Foreign Policy Behaviour) नीति-निर्णायकताओं के व्यक्तित्व की, इन लोगों पर डाले जाने वाले राजनीतिक दबावों की, राज्य की प्राथिक और सैनिक क्षमताओं की तथा

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की उपज है, तो फिर क्या हम मिदान्त की जाँच कैसे कर सकते हैं ? यह माना जा सकता है कि कुछ निर्णयों में निर्णयकर्ता का व्यक्तित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह बात भी नहीं भूली जा सकती कि दूगरे कुछ निर्णयों में उनका व्यक्तित्व बहुत ही कम महत्व रखता हो और चुनावों के समय घरेलू राजनीति का अथवा किन्हीं अन्य अवसरों पर कुछ आकस्मिक बातों का अधिक महत्व रहा हो। स्पष्ट है कि इस प्रकार की सम्भावनाओं के रहते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययनकर्ता के लिए यह काम सरल नहीं होता कि वह मिदान्तों अथवा प्राप्त प्रत्यापनाओं का मही परीक्षण कर सके। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाएँ अपनी प्रकृति में बहुकारणात्मक होती हैं और मिदान्त के परीक्षण को कठिन बना देती हैं।

सिद्धान्तों और प्राप्त प्रत्यापनाओं के परीक्षण की दूसरी सीमा यह है : सम्बन्धित सामग्री या आँकड़ों का अभाव रहता है। यहाँ हमें 'सम्बन्धित या सम्बद्ध' (Relevant) शब्दावली पर अधिक बल देना चाहिए। उदाहरणार्थ, यद्यपि चुनाव व्यवहार जैसे क्षेत्र पर सम्बन्धित सामग्री प्रभूत मात्रा में मिलती है, तथापि एक राजनीतिक वैज्ञानिक तब 'दरिद्र सामग्री वाला' (Data-poor) घन जाता है जब वह इस प्रकार की सूचना एकत्र करना चाहता हो जो यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक कर्ताओं ने अमुक व्यवहार क्यों और कैसे किया। जो सामग्री वह संकलित कर पाता है वह प्रायः उन प्रश्नों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं होती जिनमें उसकी रुचि है। उदाहरणार्थ, विदेश-नीति-निर्माण प्रक्रिया के बारे में सर्वेक्षण सामग्री (Survey Data) बहुत कम मिल पाती है। यह भी होता है कि प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित सामग्री-संकलन बहुत व्यय-साध्य और समय-साध्य हो; यह भी सम्भव है कि कुछ सामग्री प्राप्त हो न हो सके (उदाहरण के लिए, किसी सकटकाल में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के विचार)।

संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सिद्धान्तों और प्राप्त-प्रत्यापनाओं के परीक्षण में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं क्योंकि—

(अ) अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं की बहुकारणात्मक प्रकृति (Multicausal Nature) सिद्धान्तों के परीक्षण को दुरुह बना देती है।

(ब) पर्याप्त सामग्री या आँकड़ों का अभाव भी सिद्धान्तों के व्यवस्थित परीक्षण को सीमित बना देता है।

परम्परागत और सिद्धान्तों के विकास में और सिद्धान्तों के परीक्षण में कठिनाइयों का अग्रिभाष यह नहीं है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिकता को नकार रहे हैं। यह दिन-प्रतिदिन सामाजिक विज्ञानों की भाँति अधिकाधिक वैज्ञानिक अध्ययन बनती जा रही है।

विज्ञान बनाम परम्परावाद

(Science V/s Traditionalism)

आदर्शवादियों और यथार्थवादियों में चलते आ रहे विवाद के स्थान पर सन् 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में प्रमुखता उस विवाद ने ले ली जिसे मार्टन

काप्लान ने 'The New Great Debate' कहा है। यह विवाद विज्ञान और परम्परावाद के बीच है। विज्ञानवादियों अथवा व्यवहारवादियों में तथा परम्परावादियों में इस प्रश्न पर खुलकर बहस हुई है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए दोनों में से कौनसी पद्धति (Method) सर्वाधिक उपयुक्त है। यद्यपि विज्ञानवादियों और परम्परावादियों के मतभेद स्वभावतः पहले से ही चले आ रहे थे, तथापि वैज्ञानिक पद्धति को प्रथम गम्भीर चुनौती सन् 1966 में हैडले बुल (Hedley Bull) द्वारा प्रकाशित एक लेख से मिली। हैडले बुल से पहले अनेक विद्वानों ने परम्परावाद अथवा शास्त्रीय दृष्टिकोण (Classical Approach) के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन प्रस्तुत किए थे। ई. एच. कार, अल्फ्रेड जिमर्न, जॉर्ज स्वाजर्नबर्गर, हंस मॉर्गेंथो, रेमण्ड एरोन, मार्टिन ह्याइट आदि के अध्ययन इसी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। लेकिन हैडले बुल को ही यह श्रेय प्राप्त है कि उसने परम्परागत और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के सापेक्षिक गुण-दोषों पर प्रभावी ढंग से ध्यान आकर्षित किया।

बुल द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रहार
(Bull's Attack on Scientific Method)

हैडले बुल ने अपने लेख में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गिन-गिन कर प्रहार किए। उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि हाल के वर्षों में जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है उसे हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं मान सकते। बुल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरुद्ध अपने सात सुनिश्चित तर्क दिए हैं जिन्हें उसने प्रस्तावों अथवा समस्याओं के रूप में (In the Form of Propositions) प्रस्तुत किया है ताकि विद्वान् इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करके वैज्ञानिक और परम्परावादी दृष्टिकोण के बीच चल रहे विवाद की प्रकृति को समुचित रूप में समझें और अपना मत स्थिर करें।

1. बुल के अनुसार प्रथम समस्या यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-वस्तु की ऐसी प्रकृति है कि हम उसे केवल आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से नहीं जाँच सकते। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्न मुख्यतः नैतिक प्रश्न हैं जिनमें सम्प्रगु राज्यों की सरचना और उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रीय समाज में युद्ध का महत्त्व, आदि अनिश्चित प्रकृति की समस्याओं पर विचार किया जाता है। ये प्रश्न अस्थिर प्रकृति के हैं और ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिक मिद्धान्त प्रत्यक्ष रूप में नहीं अपनाते।

2. दूसरी समस्या यह है कि वैज्ञानिक विधि - प्रतिपादक अधिगणन: छोटे-मोटे सामान्य प्रश्नों के अध्ययन में ही उलझे रहे हैं। आधारभूत प्रश्न उनके अध्ययन-क्षेत्र में समुचित स्थान नहीं पा सके हैं और वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मिद्धान्त के विकास की दिशा में कोई वास्तविक योगदान नहीं कर सके हैं। उनका जो थोड़ा-बहुत योगदान है वह भी परम्परावादी पद्धति को ग्रहण करने के फलस्वरूप ही सम्भव हो सका है। इसके अनिश्चित यह योगदान भी ऐसे निर्णयों के रूप में है कि उन पर पहुँचने के लिए वास्तव में किसी भी वैज्ञानिक अथवा गणितीय पद्धतियों

की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जब हम इन निर्णयों पर बिना वैज्ञानिक पद्धति का आश्रय किए ही पहुँच सकते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का क्या उपयोग है ?

3. बुल के अनुसार तीसरी बात यह है कि वैज्ञानिक सिद्धान्तवादियों के इस दावे की भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनके अध्ययन अभी तक तो प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं, लेकिन जब शीघ्र ही वे परिपक्व अवस्था में पहुँच जाएंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सामान्य और विश्वव्यापी विज्ञान की प्रस्थापना की जा सकेगी। बुल का तर्क है कि वैज्ञानिक सिद्धान्तवादी आँकड़ों, आदि के सकलन पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं और उनके आँकड़े, आदि इतनी भारी सहायता में और इतने विभिन्न रूपों में होते हैं कि उनके आधार पर राज्य-व्यवहार (State Behaviour) का कोई सामान्यीकरण सम्भव नहीं है। आँकड़ों की दुनिया में इतना अधिक ला जाने से हम व्यावहारिक बुद्धि से काम नहीं ले सकते और सामान्य निष्कर्ष निकालने के मार्ग से भटक जाते हैं।

4. चौथी समस्या यह है कि सिद्धान्तवादियों ने अनावश्यक रूप से 'प्रतिमानों' (Models) का भ्रष्ट खंडा किया है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में यह 'मॉडलवाद' चला कर उन्होंने इस क्षेत्र में उपकार करने की अपेक्षा अपकार ही अधिक किया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-सामग्री की जो प्रकृति है उसे देखते हुए मॉडल-निर्माण अनावश्यक है। इससे विषय-वस्तु को तमकने में हमें कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि हम चक्कर में पड़ जाते हैं। मॉडल-निर्माण बहुधा मयार्य की उपेक्षा कर देता है और सब चीजों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से आँकता है। मॉडल-निर्माण की प्रक्रिया राज्य-व्यवहार की वास्तविकता से इतनी दूर होती है कि उसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को सही रूप में नहीं समझा जा सकता। ऐसे मॉडलों पर विश्वास करना सही मार्ग से भटकना है।

5. बुल की पाँचवीं आपत्ति यह है कि वैज्ञानिक पद्धति को व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति वैज्ञानिक उपकरणों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें एक तरह की घुन सवार हो जाती है और वे उन धुन में डूबे हुए व्यावहारिकता तथा वास्तविकता से अलग हट जाते हैं। वैज्ञानिक सिद्धान्तवादियों का एकमात्र उद्देश्य परिशुद्धता और मात्रानुकरण (Precision and Quantification) प्राप्त करना होता है; अतः वे विभिन्न समाजों के सापेक्ष अन्तरों की उपेक्षा कर बैठते हैं।

6. बुल के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सिद्धान्तों में यद्यपि परिशुद्धता (Precision) की महती आवश्यकता है, लेकिन यह परिशुद्धता वैज्ञानिक सिद्धान्तवादियों की परिशुद्धता से भिन्न है। वैज्ञानिक सिद्धान्तवादी परिशुद्धता का एक सीमित दृष्टिकोण अपनाते हैं और अपने द्वारा एकत्र आँकड़ों एवं तथ्यों के सन्दर्भ में ही परिशुद्धता पर जोर देते हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में परिशुद्धता ऐसी होनी चाहिए जो अध्ययन की सम्पूर्ण विषय-वस्तु को अपने में समेट ले। बुल का विश्वास है कि इस प्रकार की परिशुद्धता केवल परम्परावादी दृष्टिकोण की सहायता

से ही सम्भव है। बुल ने यह स्वीकार किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सिद्धान्त अवश्य ही वैज्ञानिक होना चाहिए किन्तु केवल इसी अर्थ में यह ज्ञान का एक सुसंगत, सक्षिप्त और व्यवस्थित निकाय हो तथा आधुनिक विज्ञान की दार्शनिक आधार-शिलाओं के अनुकूल हो।

7. बुल द्वारा प्रस्तुत अन्तिम तर्क यह है कि वैज्ञानिक पद्धति के समर्थकों ने अपने आपको इतिहास और दर्शन से पृथक् कर लिया है जबकि इनके माध्यम से हम आत्म-विवेचन कर सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धान्तवादी आधुनिक इतिहास की अवस्थाओं को जानने की चेष्टा नहीं करते जबकि ये अवस्थाएँ ही अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की वर्तमान अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाली हैं।

परम्परावाद पर प्रत्याक्रमण

(Counter-attack on Traditionalism)

हैडले बुल ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परम्परावादी अध्ययन पर बल देते हुए वैज्ञानिक पद्धति पर जो तीव्र प्रहार किए हैं उनकी गम्भीर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। यद्यपि वैज्ञानिक पद्धति के अनेक समर्थकों ने बुल के आक्रमण के विरुद्ध अपना बचाव किया, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली बचाव-पक्ष मार्टन काप्लान की ओर से प्रस्तुत हुआ। उसने अपने विख्यात लेख 'The New Great Debate Traditionalism V/s Science in International Relations' में बुल द्वारा समर्थित परम्परावाद पर एक प्रकार से जबरदस्त प्रत्याक्रमण किया और बतलाया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति क्यों अधिक सहायक है। मार्टन काप्लान ने जो तर्क प्रस्तुत किए वे संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं—

1. काप्लान ने सबसे पहले परम्परावादियों की इस धारणा को आड़े हाथों लिया है कि हम वैज्ञानिक पद्धति द्वारा नहीं बल्कि अन्य पद्धतियों से मानव-उद्देश्य (Human Purpose) को समझ सकते हैं। काप्लान के अनुसार यह धारणा इस विश्वास पर आधारित है कि मानव-उद्देश्य परीक्षण अथवा सत्यापन (Verification) की अपेक्षा प्रयोजनों (Motives) से अधिक सम्बन्धित है जिनका सफलतापूर्वक विश्लेषण केवल सहज-ज्ञान और अन्तर्दर्शन अथवा आत्म-निरीक्षण द्वारा ही किया जा सकता है। काप्लान का मत है कि यद्यपि यह ठीक है कि मानव-उद्देश्य प्रयोजनों (Motives) से सम्बन्धित है, लेकिन इन प्रयोजनों की पुष्टि लोगों के व्यवहार-आदर्शों (Behaviour Patterns) के समुचित निरीक्षण और विश्लेषण से ही हो सकती है। हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को सीधे व्यक्तिगत प्रयोजनों से नहीं आँक सकते। काप्लान को यह आरोप भी मान्य नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में अपेक्षित परिशुद्धता और मात्रानुकरण (Precision and Quantification) वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। काप्लान का निश्चित मत है कि कोई भी सिद्धान्त अनुशासन की दशा और विषय-वस्तु के स्वरूप दोनों पर निर्भर करता है।

2. परम्परावादियों का यह विचार बहुत ही पिछड़ा हुआ और 17वीं शताब्दी का विचार है कि राजनीतिक जगत् में घटने वाली घटनाओं का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता। आज का युग विज्ञान का युग है, हर क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन अपना चमत्कार दिखा रहा है और राजनीतिक क्षेत्र इसका अपवाद नहीं है।

3. परम्परावादियों की इस धारणा में भी कोई बल नहीं है कि वैज्ञानिक सिद्धान्तवादी अपने मॉडलों को सही अथवा यथार्थ मानने की भूल करते हैं। वैज्ञानिक सिद्धान्तवादियों का तर्क है कि इस प्रकार का खतरा तो प्रत्येक प्रकार की मानव-गतिविधियों में होता है। चाहे वैज्ञानिक हो या समाजशास्त्री अथवा मानवशास्त्री, सभी इस प्रकार की भूल के शिकार बनते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत अवधारणाएँ भी अनेक बार वास्तविकता से मेल नहीं खाती। काप्लान का तो विश्वास है कि मॉडलों को वास्तविकता मान लेने की भूल का दोषारोपण विज्ञानवादियों पर बस्तुनः उतना लागू नहीं होता जितना परम्परावादियों पर। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीतिक इतिहास के विशाल साहित्य पर दृष्टिपात करें तो हमें ऐसे ढेर के ढेर उदाहरण मिल जाएँगे जो यह सिद्ध करने के लिए काफी हैं कि परम्परावादियों द्वारा मानव-प्रयोजनों और अन्तर्सम्बन्धों के बारे में कितनी भ्रामक अवधारणाएँ निरूपित की जाती रही हैं। काप्लान के अनुसार परम्परावादियों का दोष यह है कि वे प्रमाण (Evidence) के महत्व की जानबूझ कर उपेक्षा करते हैं जबकि विज्ञानवादी इसकी सार्थकता में पूरा विश्वास रखते हैं।

4. परम्परावादियों का यह आरोप भी गलत है कि विज्ञानवादी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में दर्शन (Philosophy) की पूर्ण उपेक्षा करते हैं। काप्लान तो उल्टे यह आरोप लगाता है कि सिवाय रेमण्ड एरोन के अन्य परम्परावादियों ने दर्शन का समुचित रूप से 'अनुशासित अनुमान' (Disciplined Speculation) के रूप में प्रयोग किया है। काप्लान का दावा है कि अनेक ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आधारभूत रूप में दार्शनिक हैं और व्यवस्थावादी सिद्धान्त (System Theory), जो कि वैज्ञानिक पद्धति का एक भाग है, उनसे घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। वास्तव में वैज्ञानिक सिद्धान्तवादियों ने दार्शनिक प्रश्नों को अथवा दर्शन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की दृष्टि से जितने सुव्यवस्थित रूप में और जितनी गम्भीरता से लिया है उतने अच्छे ढंग से स्वयं परम्परावादी, जो दर्शन की वकालत करते हैं, नहीं ले पाए हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का सुनिश्चित मत है कि चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी अन्य किसी सामाजिक गतिविधि की भांति मनुष्यों से सम्बन्धित है, अतः मनुष्यों के व्यवहार के विश्लेषण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का समुचित रूप में अध्ययन हो सकता है। आखिर मानव-व्यवहार ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में मनुष्यों की गतिविधियों को प्रतिबिम्बित करता है। वैज्ञानिक अथवा व्यवहारवादी दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग का पोषक है

और इसका आग्रह है कि सामाजिक रूप में परिभाषित भूमिकाओं में लोगों के व्यवहार का अध्ययन ही हमारा केन्द्रीय उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक विज्ञान के विभिन्न शास्त्रों—विशेषकर समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान और मानव-शास्त्र की ओर अपना कदम बढ़ाएँ क्योंकि ये सब शास्त्र मानव-व्यवहार को समझने में हमारी मदद करते हैं। निरन्तर परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक सत्ता के वितरण की उचित जानकारी के लिए इन सामाजिक विज्ञानों का सहारा लेना आवश्यक है क्योंकि इनके आधार पर ऐसे सिद्धान्तों का निर्माण किया जा सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वानुमान में सहायक सिद्ध हो सकें और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का समुचित अध्ययन करने की दिशा में हमें आगे बढ़ा सकें। यद्यपि परम्परावादी भी अन्य शास्त्रों के अध्ययन को आवश्यक मानते हैं, लेकिन उनका आग्रह इतिहास, कानून और दर्शन पर है। विज्ञान बनाम परम्परावाद (Science V/s Traditionalism) का संघर्ष जारी है तथापि आधुनिक प्रवृत्ति विज्ञानवाद की ओर है और विज्ञानवादियों अथवा व्यवहारवादियों का विश्वास है कि एक दिन वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 'सामान्य सिद्धान्त' (General Theory) का निर्माण कर सकेंगे।



अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति-संघर्ष के रूप में : राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा

(International Politics as a Struggle for Power : Concept of National Power)

“अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता, वह विशाल हो सकता है, धनवान हो सकता है और महान् भी हो सकता है, किन्तु वह शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा।” —घार्गेन्सकी

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की एक बड़ी कठिन समस्या यह स्पष्ट करना है कि एक राष्ट्र ने जिस रूप से व्यवहार किया है, उसने उसी रूप में क्यों किया अन्य रूपों में क्यों नहीं किया। विचारकों ने इसके अनेक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं। किसी ने ‘शक्ति’ को प्रमुखता दी है तो किसी ने ‘राष्ट्रीय हित’ को, जबकि कुछ ने दोनों को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया है। ऐसे भी विचारक हैं जो विचारधारा को राष्ट्रीय व्यवहार की सबसे अधिक प्रेरक-शक्ति मानते हैं। कतिपय व्यक्ति राष्ट्रीय व्यवहार का बौद्धिकरण उस राष्ट्र के उपलब्ध साधनों, महत्वाकांक्षाओं, राष्ट्रीय चरित्र, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, आदि के आधार पर करने का प्रयास करते हैं, किन्तु आधुनिक प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति (Power) के आधार पर समझने की है। अधिक विद्वान् यह मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्पन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, प्राप्त शक्ति की वृद्धि करने, उसका प्रदर्शन करने आदि से सम्बन्ध रखता है। हेराल्ड स्प्राउट तथा मार्ग्रेट स्प्राउट (Harold & Margaret Sprout) ने लिखा है—

“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली में सर्वाधिक बहु-प्रयुक्त शब्दों में से एक है पावर (शक्ति)। राज्यों को शक्तियाँ कहा जाता है और उनका वर्गीकरण महाशक्ति (सुपर पावर), विश्व-शक्ति (वर्ल्ड पावर), बड़ी शक्ति (ग्रेट पावर), दूसरे नम्बर की शक्ति (सैकेंड रेट पावर), कमजोर शक्ति (वीक पावर) आदि किया

जाता है। राजनेता पूरा ध्यान शक्ति-सन्तुलन पर देते हैं। शक्ति-सन्तुलन ठीक करने, शक्ति में वृद्धि करने या अन्य प्रकार से राज्य की शक्ति-स्थिति सुधारने के लिए गठबन्धन किए जाते हैं। ऐसी क्रियाओं को 'शक्ति की राजनीति' कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुधा परिभाषा ही 'शक्ति के लिए संघर्ष' के रूप में की जाती है। पारम्परिक राजनीतिक क्रिया धरेलू हो या अन्तर्राष्ट्रीय, उसके प्रायः हर वर्णन की तह में शक्ति का कोई सम्प्रत्यय होता है। राजनीतिशास्त्र के अनुशासन की परिभाषा 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र जिसकी एक शाखा है—समाज में शक्ति का अध्ययन'—के रूप में की गई है।¹

चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या अन्तर्राष्ट्रीय, शक्ति-तत्त्व दोनों में सन्निहित होता है। इसका कभी विलोप नहीं होता। अवश्य ही शिथिलता और तीव्रता की लहरे आती-जाती रहती हैं। स्प्राउट एव स्प्राउट (Sprout & Sprout) ने एक अमेरिकी इतिहासवेत्ता काले बेकर के सारगर्भित कथन को प्रस्तुत करने हुए लिखा है—

"सामान्य तथ्य यह है कि राजनीति को शक्ति में अलग नहीं किया जा सकता। राज्यों और सरकारों का अस्तित्व ही शक्ति-प्रयोग के लिए होता है। प्रत्येक देश में और आम तौर पर विश्व में या तो शक्ति-सन्तुलन स्थिर होता है या अस्थिर या विन्तुल नहीं होता लेकिन शक्ति सदा रहती है। समार में राजनीतिक शक्ति का अस्तित्व है और जिनके पाम वह है वे उसका प्रयोग भी करेंगे।"²

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रख्यात विद्वान् हंस जे मॉर्गेन्थो (Hans J. Morgenthau) ने तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया है। तदनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष (Struggle for Power) है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्तर्निहित तत्त्व चाहे कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, उसका तत्कालीन लक्ष्य शक्ति प्रदान करना ही होता है।"³ अतः यदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मर्म को समझना है और उसकी गूढ़ता को हृदयगत करना है, तो हमें शक्ति की महत्ता अर्थात् राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा (Concept of National Power) को समझना होगा।

राष्ट्रीय शक्ति क्या है ?

(What is National Power?)

कतिपय प्रमुख परिभाषाएँ

(Some Important Definitions)

दूरों को प्रभावित कर सकने की क्षमता को साधारणतया हम 'शक्ति' के नाम से सम्बोधित करते हैं। यदि शक्ति को व्यक्तिगत शक्ति के मन्दर्भ में न लेकर

1 Harold Sprout & Margaret Sprout : Foundations of International Politics (Hindi ed.), p. 183.

2 Quoted by Sprout & Sprout : Ibid, p. 183.

3 Hans J. Morgenthau : op. cit., p. 25.

हम राष्ट्रीय सन्दर्भ में लें तो उसे 'राष्ट्रीय शक्ति' कहेंगे। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का एक ऐसा अस्त्र है जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में उसका स्तर, महत्त्व एवं स्थान प्राप्ति जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति उस मापदण्ड का कार्य करती है जिसके आधार पर हम अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर पड़ने वाले किसी राष्ट्र के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं और इस प्रकार अन्य विषयों को भी अपनी विदेश-नीति में तदनुकूल समायोजन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को एक राष्ट्र का सबसे बड़ा केन्द्र-बिन्दु माना है जिसके चारों ओर उसकी विदेश-नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते रहते हैं। राज्य का सबसे बड़ा हित यह है कि वह अधिकाधिक राष्ट्रीय शक्ति का अर्जन करे, जिन साधनों और तत्वों द्वारा राष्ट्र की शक्ति बढ़ाई जा सकती है उनकी ओर पर्याप्त ध्यान दे और उनके विकास, अभिवर्द्धन, संरक्षण, संपोषण, प्रादि पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करे। यदि राष्ट्र विपरीत आचरण करते हुए अपनी राष्ट्रीय शक्ति को क्षीण होने देता है तो इसका स्पष्ट आशय 'आत्मघात' है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मथार्थवादी सिद्धान्त, जिसका पिछले अध्याय में विस्तार से विवेचन किया जा चुका है, इसी बात पर बल देता है कि प्रत्येक राष्ट्र 'शक्ति के रूप में परिभाषित हित' (Interest Defined in Terms of Power) की दृष्टि से ही सोचता है।

राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा को विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। कुछ प्रमुख विचारों और परिभाषाओं पर विचार करना उपयुक्त होगा—

स्प्रौट एवं स्प्राउट—हेराल्ड तथा मॉर्गेट स्प्रौट ने राजनीतिक शक्ति की अवधारणा को समझते हुए राष्ट्रीय शक्ति को स्पष्ट किया है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति का विवेचन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रामाणिक है।¹ स्प्रौट के अनुसार राजनीतिक शक्ति की धारणा परिमाण उपकरण के स्थान पर व्यवहारगत सम्बन्धों की होती जा रही है। राजनीतिक शक्ति के सम्प्रत्यय की इस अवधारणा को समझने के लिए स्प्रौट ने सेमुअल एच बिमर की निम्नलिखित परिभाषा उद्धृत की है—

“एक व्यक्ति दूसरे पर शक्ति प्रयोग करता है जबकि वह जानबूझ कर ऐसे तरीके से काम करे जिससे दूसरे का कार्य भविष्यवाणी करने योग्य ढंग से प्रभावित हो... शक्ति समाज में कई रूप धारण करती है। एक स्पष्ट रूप है सम्पदा। हममें से प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के इस रूप का प्रयोग वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करके करता है। शक्ति के अन्य परिचित रूप हैं—जारीरिक शक्ति, सामाजिक हैसियत, शिक्षा, नैतिक आचरण, व्यक्तिगत आकर्षण, फौजी, कानूनी या प्रबन्ध की योग्यता। बहुधा हम एक व्यक्ति की दूसरे पर शक्ति का श्रोत इन कारणों में से एक या अनेक के रूप

में खोज सकते हैं जो उसका 'शक्ति-आधार' है। इस प्रकार 'शक्ति के आधार' की चर्चा का अर्थ यह नहीं है कि शक्ति कोई ऐसी चीज होती है जो किसी व्यक्ति या गुट के पास ही है। शक्ति सापेक्ष होती है। एक व्यक्ति का दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव केवल शक्ति रखने वाले पर ही नहीं, उस व्यक्ति पर भी निर्भर है जिसे प्रभावित किया गया है। प्रभावित व्यक्ति की स्थिति में अवश्य अन्तर पड़ जाएगा। सम्पन्न की तुलना में शायद गरीब आदमी, धन के प्रभाव में अधिक आ जाएगा। हथियारबन्द व्यक्ति की तुलना में इसी प्रकार निहत्था व्यक्ति हथियार के प्रभाव में अधिक आ जाएगा। इनके अलावा जिसे प्रभावित करना अभीष्ट है उस व्यक्ति के स्वार्थ और मनोवैज्ञानिक धारणा भी परिणाम पर असर डालेंगे। शहीद को हिंसा का डर, भूख को तर्क ही अपील, नास्तिक को स्वर्गीय सुख का आश्वासन दिगा नहीं सकेगा। जहाँ ये व्यक्तिगत रुझानों के उदाहरण हैं, इनसे यह भी पता चलता है कि एक समाज की संस्कृति उनके भीतर उभरने वाली शक्ति के रूपों पर किस प्रकार गहरा प्रभाव डालती है।"

विषय के इस शक्ति-विवेचन को स्प्राउट एव स्प्राउट ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रासंगिक मानते हुए लिखा है—“मुख्य सम्प्रत्यय परस्पर त्रिया का है। पारस्परिक त्रिया का मर्म है, माँग और प्रतिक्रिया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में माँग करने वाले होते हैं राज्य के सरकारी प्रतिनिधि या प्रवक्ता—वह व्यक्ति या गुट जिन्हें राज्य के नाम पर बदम उठाने का कानूनी अधिकार मिला होता है। उनकी माँगों का राजनीतिक महत्त्व तभी होगा जब उनके फलस्वरूप कुछ विरोध उत्पन्न हो, कुछ प्रतिरोध हो, कुछ स्वार्थ-सर्पथ सामने आएँ। लेकिन माँग हो या प्रतिक्रिया—उसे राजनीतिक होने के लिए युद्धरत या युद्ध की सम्भावना दिखाना आवश्यक नहीं है। माँगें विनम्र या आदेशपूर्ण, अत्यन्त स्पष्ट या अस्पष्ट और सामान्य प्रकार की हो सकती हैं। प्रतिक्रियाएँ भी मंत्रीपूर्ण या नाराजी की स्थिति में हर सम्भव प्रतिरोध के बीच, कही भी हो सकती हैं।”

स्प्राउट एवं स्प्राउट महोदय ने 'क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति' पर अपनी सुविख्यात पुस्तक के अध्याय चार में अपने विचार विस्तार से प्रकट किए हैं। इस सम्बन्ध में उनके विचारों के सारांश को हम इसी अध्याय में आगे 'क्रियाशील राष्ट्रीय शक्ति' के शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत करेंगे।

मॉर्गेंथो—यथार्थवादी सिद्धान्त के प्रतिपादक मॉर्गेंथो के मतानुसार राष्ट्रीय शक्ति “राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियन्त्रण रखने की चेष्टा करता है।” यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर एक व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा लेता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति दूसरे के मन और विचारों को प्रभावित कर उनमें अपना वांछित कार्य करा लेता है। राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा के साथ मॉर्गेंथो का नाम सुप्रतिष्ठित रूप में जुड़ा

हुआ है और उनके विचारों पर भी विस्तार से आगे एक पृथक् जीर्णक में प्रकाश डाला गया है ।

पंडलफोर्ड तथा लिंकन—इन लेखक द्वय का मत है कि "यह शब्द राष्ट्रीय शक्ति की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है । किन्तु उस व्यापक अर्थ में, जिसमें यह शब्द अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य शक्ति-सम्पर्क में प्रयुक्त किया जाता है, यह इससे अधिक व्यापक है । राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति एवं सामर्थ्य का वह योग मान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है ।"¹

शूमा—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वाति-प्राप्त विद्वान् शूमा ने लिखा है कि वह शक्ति, जिसको अपने राज्य में उत्सुकतापूर्वक सुरक्षित रखना और दूसरों में व्यग्रतापूर्वक देखना आवश्यक होता है, अन्तिम विश्लेषण में सैनिक शक्ति अथवा वौद्धिक योग्यता है । शक्ति का स्वतः अर्थ मित्रों को प्राप्त करने और लोगों को प्रभावित करने, सहानुभूति जाग्रत करने, आज्ञापालन तथा सहयोग प्राप्त करने वाले भौतिक साधनों एवं धूर्ततापूर्ण उपायों द्वारा दृढ़तापूर्वक कार्य लेने की योग्यता ही है । लेकिन वह शक्ति जो मुख्यतः एक राजसत्ता के अन्य राजसत्ताओं से व्यवहार करने से सम्बन्ध रखती है, एक सुसंगठित ढाँचे के अन्तर्गत कार्य करने वाले राजनीतिज्ञों, राजनीतिक दलों, दबाव-समुदायों, गोष्ठी-गृहों और मतदाताओं की शक्ति की प्रवेक्षा एक सरल, अधिक सीमित एवं अधिक अनिश्चित गुण है । यहाँ शक्ति का आश्रय लेने का अवसर कम हो जाता है और वस्तुतः शक्ति पर एकाधिकार रखने वालों द्वारा बल-प्रयोग को दृढ़तापूर्वक रोक दिया जाता है । कपट और अनुग्रह, विचार-शक्ति और आकांक्षा के प्रति अपील का नियमित परिस्थितियों में प्राधान्य रहता है । किन्तु स्वतन्त्र राज्यों के प्रभाव के ये साधन प्रायः महत्वपूर्ण होते हुए भी विस्तार और गुण की दृष्टि से सीमित होते हैं । एक सम्राट् की दूसरे सम्राटों के साथ व्यवहार करने की अन्तिम युक्ति शक्ति ही है ।²

हार्टमैन के शब्दों में, "राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है ।"³ आर्गेन्सकी का मत है कि "अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है । जब तक कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता तो वह विनाश, धनवान् और महान् होते हुए भी शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा ।"⁴

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय शक्ति के अनिवार्यतः दो उद्देश्य होते हैं—(क) आत्म-रक्षा, एवं (ख) अपने प्रभाव का विस्तार ।

1 *Padleford & Lincoln* : International Politics, p. 193.

2 *Schuman* : International Politics, p. 250

3 *Hartmann* : The Relations of Nations, p. 10.

4 *Organsky* : World Politics, p. 96.

राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राज्य का न्यूनतम दायित्व है। इसके लिए उसे शक्ति-सम्पन्न होना ही पड़ता है। लेकिन कई राष्ट्र केवल अपनी सुरक्षा से ही सन्तुष्ट नहीं रहते, अतएव दूसरे राष्ट्रों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना महत्त्व बढ़ाना चाहते हैं। इस महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति सभी सम्भव है जब वह राष्ट्र विपुल साधन-सम्पन्न हो। साधनों से अभिप्राय धन, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, मैन्य-शक्ति आदि विभिन्न बातों से है जिनका विस्तार से विवेचन अगले अध्याय में किया गया है। यहाँ इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि साधनों की प्रचुरता होते हुए भी यह आवश्यक नहीं है कि कोई राष्ट्र अनिवार्य रूप से शक्तिशाली भी है अर्थात् इस बात में समर्थ है कि दूसरे राष्ट्रों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में ला सके। वास्तव में जब तक किसी राष्ट्र में अपने साधनों को समुचित रूप से प्रयुक्त कर अपने प्रभाव का विस्तार करने की कला अथवा सामर्थ्य न हो तब तक साधन-सम्पन्न होते हुए भी वह शक्ति-सम्पन्न नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, सन् 1947 तक चीन विशाल भू-भाग, विशालतम जनसंख्या और बड़ी भारी सेना रखते हुए भी बड़े राष्ट्रों में नहीं गिना जाता था जबकि आज स्थिति सर्वथा विपरीत है। इसी प्रकार अरब राष्ट्रों के पास विपुल तेल-शक्ति है, लेकिन उनमें दूसरे राष्ट्रों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लेने की शक्ति का अभाव है। आशय यह है कि शक्ति-सम्पन्न बनने के लिए साधनों के समुचित उपयोग द्वारा दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करने की इच्छा और सामर्थ्य भी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि शक्ति के अस्तित्व का मुख्य आधार यह है कि राष्ट्रों के मध्य किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध विद्यमान हो और जहाँ वही दो राष्ट्रों के बीच आपसी सहमति न हो, वहाँ एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने अनुकूल व्यवहार के लिए प्रभावित करने की योग्यता रखता हो। उदाहरणार्थ, द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने रूसी प्रभाव-विस्तार को रोकने के लिए पश्चिमी जर्मनी के सैन्यीकरण करने की इच्छा प्रकट की थी। लेकिन फ्रांस ने, जो रूस की अपेक्षा सदैव जर्मन सेनाओं से भयभीत रहा है, इसका विरोध किया तथा गुप्त रूप से अनेक कूटनीतिक कदम उठाए परन्तु अन्त में वह पश्चिमी जर्मनी के सैन्यीकरण के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर कहा जा सकता है कि अमेरिका ने फ्रांस पर अपनी 'शक्ति का प्रयोग किया अर्थात् वह फ्रांस को अपने प्रभाव में ला सका।

राष्ट्रीय शक्ति पर मॉर्गेंथो के विचार (Morgenthau's Views on National Power)

राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा के साथ मॉर्गेंथो का नाम सुप्रतिष्ठित रूप में जुड़ा हुआ है। अतः उनके विचारों को कुछ विस्तार से जान लेना उपयुक्त होगा। मॉर्गेंथो ने प्रथम तो यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्र क्या है और तदुपरान्त बतलाया है कि हम राष्ट्रीय शक्ति को कैसे मापें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शक्ति की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है तथा एक राष्ट्र के निवासी उसकी अनुभूति से

रोमांचित हो उठते हैं। अग्रिम पंक्तियों में हम मॉर्गेंथो के स्वयं के शब्दों में¹ सारांश में उनके विचार प्रस्तुत करेंगे।

“राष्ट्र स्वयं में एक वस्तु तो है नहीं जिसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। राष्ट्र तो उन तमाम व्यक्तियों का अदृश्य अथवा अमूर्त रूप है जिनके कुछ लक्षण सामान्य हैं और उन लक्षणों के कारण ही वे सब एक राष्ट्र के सदस्य बनते हैं। इसीलिए जब हम व्यावहारिक रूप में किसी राष्ट्र की शक्ति अथवा वैदेशिक नीति की बात कहते हैं तो हमारा अर्थ केवल उन विशेष व्यक्तियों की शक्ति अथवा विदेश-नीति से होता है जो उसी राष्ट्र के सदस्य हैं।”

“परन्तु इससे एक दूसरी कठिनाई पैदा हो जाती है। संयुक्तराज्य की शक्ति तथा विदेश-नीति स्पष्ट रूप से उन तमाम व्यक्तियों की शक्ति तथा नीति नहीं है जो उस राष्ट्र के सदस्य हैं जिसे ‘संयुक्तराज्य’ कहा जाता है। यह तथ्य कि द्वितीय विश्व-महायुद्ध के उपरान्त संयुक्तराज्य विश्व में सर्वशक्तिमान राष्ट्र होकर उभरा है, अमेरिकी जनता के बहुत से व्यक्तियों की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं ला सका है परन्तु उसने उन तमाम व्यक्तियों की शक्ति में परिवर्तन ला दिया है जो संयुक्तराज्य के वैदेशिक मामलों का निपटारा करते हैं। चूंकि कोई राष्ट्र अपनी विदेश-नीति का संचालन एक कानूनी सत्ता के रूप में करता है जिसे राज्य कहा जाता है एवं जिसके प्रतिनिधि राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उसकी ओर से बोलते हैं, उसके नाम से सन्धिपत्रा करतें हैं और उसकी शक्ति स्थापित, परिवर्द्धित अथवा प्रदर्शित करते रहते हैं। ये व्यक्ति ही राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपने राष्ट्र की नीतियों का अनुसरण करते हैं। जब कभी भी हम व्यावहारिक रूप में किसी राष्ट्र की शक्ति अथवा विदेश-नीति का प्रश्न उठाते हैं, तब हमारा तात्पर्य इन्हीं व्यक्तियों से होता है।”

“तो फिर यह कैसे सम्भव हो जाता है कि राष्ट्र के वे बहुसंख्यक जन जिनकी व्यक्तिगत शक्ति राष्ट्रीय शक्ति के भाग्य के उलटफेर से प्रभावित नहीं होती, राष्ट्र की शक्ति अथवा उसकी विदेश-नीति से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं तथा उस शक्ति को बिल्कुल अपनी ही अनुभव करते हैं। यह सब उस प्रेरणा तथा भावात्मक अनुभूति की गहराई से करते हैं जिसका लगाव उनकी स्वयं की व्यक्तिगत शक्ति की आकांक्षाओं से भी कहीं अधिक गहरा और परे होता है? यह प्रश्न उठाकर हम वास्तव में आधुनिक राष्ट्रवाद की समस्या का प्रश्न उठा रहे हैं।”

होता यह है कि अधिकांश व्यक्ति राष्ट्रीय समुदाय के भीतर अपनी शक्ति-लिप्ता को शान्त करने में असफल रहते हैं। जन-साधारण का एक बहुत बड़ा समूह बहुत सीमा तक केवल शक्ति का लक्ष्य-मात्र रहता है, स्वयं शक्ति उपार्जन करने

वाला नहीं होता। अपनी शक्ति-लोलुपता की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय परिधि के अन्तर्गत पूर्ण तृप्ति प्रदान करने में सफल न होने के कारण जनता इन असंतुष्ट आकांक्षाओं को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सक्रमित कर देती है। वहाँ राष्ट्र की शक्ति की आकांक्षाओं से तादात्म्य करके अप्रत्यक्ष तृप्ति का अनुभव करता है। जब भी संयुक्तराज्य का नागरिक अपने देश की शक्ति के बारे में सोचता है, तो उसे उसी प्रकार की उच्चता का अनुभव होता है जो कि रोम के नागरिक को रोम तथा उसकी शक्ति से तादात्म्य करने के उपरान्त अनुभव होता होगा और उसी आधार पर वह विदेशियों से घृणा करता होगा। जब हम अपने आपको एक ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र का सदस्य अनुभव करते हैं जिसकी औद्योगिक सामर्थ्य तथा भौतिक वैभव अद्वितीय है, तो हमें उच्चता की अनुभूति होती है और हम बहुत गर्व अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब व्यक्तिगत तौर पर नहीं बरन् सामूहिक तौर पर एक ही राष्ट्र के सदस्य होने के नाते इस महान् शक्ति पर प्रभुत्व तथा नियन्त्रण स्थापित करते हैं। जो शक्ति हमारे प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उपभोग करते हैं, वह हमारी अपनी ही प्रतीत होने लगती है और जो विफलताएँ हम राष्ट्रीय समुदाय के अन्दर अनुभव करते हैं, उनकी पूर्ति राष्ट्र की शक्ति के आनन्ददायक उपभोग द्वारा हो जाती है। चूँकि ऐसे मामलों में पूर्ण मतैक्य असम्भवप्राय है, अतः जनता में कुछ वर्ग तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने राष्ट्र की शक्ति या आकांक्षाओं के पूर्ण समर्थक होते हैं और कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं जो इस बात से सम्बन्ध नहीं रखते अथवा कुछ अन्य शिथिल विचार रखते हैं।

राष्ट्रीय शक्ति की मॉर्गेंथोवादी व्याख्या को सरल शब्दों में यों प्रकट किया जा सकता है कि राष्ट्र की विदेश-नीति का संचालन एवं राष्ट्र की शक्ति का प्रयोग प्रत्येक निवासी की सामर्थ्य एवं योग्यता के बाहर का विषय है। यह उस राष्ट्र के चुने हुए नेताओं के हाथ में रहती है और इसीलिए एक राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि का तात्पर्य यह नहीं होता कि अब उसका प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली हो गया है, किन्तु केवल वे लोग ही जो अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर होने वाले अभिनय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, एक राष्ट्र की बढ़ती हुई शक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं। यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतवर्ष का स्थान ऊँचा है तो निश्चय ही उसके राजनीतिज्ञों का स्थान भी सम्माननीय एवं उत्कृष्ट समझा जाएगा। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब एक व्यक्ति पर उसके राष्ट्र की शक्ति एवं विदेश-नीति का गीघा प्रभाव नहीं पड़ता तो वह किस आधार पर अपने आप को उसके समरूप मान लेता है। इस प्रश्न का उत्तर एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा दिया जा सकता है जिसके अनुसार अधिकांश व्यक्तियों को उनके राष्ट्रीय जीवन में कोई सम्मान और इज्जत प्राप्त नहीं हो पाती जिसके लिए वह सदैव प्रयत्न करता रहता है। अपने इस अभाव की पूर्ति वह दूसरे रूप में कर लेता है अर्थात् उसके देश के प्रतिनिधियों को अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में जो सम्मान प्राप्त होना है उसको वह स्वयं का सम्मान मान लेता है। जिस शक्ति को व्यक्तिगत जीवन में एक बुराई माना जाता है तथा जिसे प्रजातन्त्र, समानता व

स्वतन्त्रता के विरुद्ध माना जाता है, उसी शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तथा शक्ति प्राप्त करने के सभी प्रयासों को व्यापकित ठहराया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति के साथ अपनी शक्ति का तादात्म्य करने वाले लोग प्रायः मध्यमवर्गीय परिवारों के होते हैं जिनके पास शक्ति की मात्रा अपर्याप्त रहती है तथा जो अपने आपनों अरक्षित अनुभव करते हैं।

अन्त में उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शक्ति का रूप एवं स्तर का निर्धारण हमेशा तुलनात्मक रूप से ही किया जाता है। एक राष्ट्र कमजोर है यह कहते समय हमारे मस्तिष्क में एक दूसरे राष्ट्र का चित्र भी रहता है जो इससे अपेक्षाकृत शक्तिशाली होता है। इसी प्रकार एक राष्ट्र को शक्तिशाली कहते समय हमारे ध्यान में कमजोर राष्ट्र की मूर्ति भी रहती है। इस प्रकार की तुलना करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्त्व की तुलना दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के उसी तत्त्व के साथ ही कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएँ

(Characteristics of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति के विचार को हम राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताओं के आधार पर और अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

- (1) अस्थायी चरित्र,
- (2) सापेक्षता,
- (3) तुलात्मक स्वरूप,
- (4) शक्ति की दृष्टि से राष्ट्रों में असमानता,
- (5) सभी तत्त्वों का समान महत्त्व,
- (6) राष्ट्रीय शक्ति के सही मूल्यांकन की कठिनाई।

अस्थायी चरित्र—राष्ट्रीय शक्ति के चरित्र में कोई स्थायित्व नहीं पाया जाता और समय-समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। भारत की राष्ट्रीय शक्ति का जो स्वरूप अथवा चरित्र पहले था वह आज नहीं है। सैनिक दृष्टि से निर्वल और अपनी सुरक्षा के प्रति प्रकाशित भारत आज सैन्य-बल, प्रभाव तथा सुरक्षा की दृष्टि से आत्म-विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र है। सन् 1947 में चीन की राष्ट्रीय शक्ति का जो स्वरूप था, उसकी तुलना में आज वह विश्व की एक बड़ी शक्ति है। उसका विशाल भू-भाग लगभग वही है, जनसंख्या भी योड़ी-बहुत ही बढ़ी है, लेकिन सैन्य बल, गुण और सत्ता की दृष्टि से, प्रहार-क्षमता की दृष्टि से, बहुत वृद्धि हुई है। कूटनीतिक कौशल, विस्तारवादी महत्वाकांक्षा, नित्यप्रति बढ़ती हुई सैनिक शक्ति आदि के बल पर वह बहुत से राष्ट्रों पर अपने प्रभाव का विस्तार करने में सफल हुआ है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय शक्ति का जो स्वरूप दिसम्बर, 1971 से पूर्व था वह आज नहीं है। तथाकथित पूर्वी पाकिस्तान स्वतन्त्र बंगला देश के रूप में जन्म ले चुका है और विखण्डित पाकिस्तान की स्थिति आज दयनीय है। संक्षेप में, राष्ट्रीय

शक्ति का स्वरूप समय-समय पर बदलता रहता है। जापान, जर्मनी आदि के उदाहरण राष्ट्रीय शक्ति के अस्थायी चरित्र के अन्य उवलन्त प्रमाण हैं।

सापेक्षता—राष्ट्रीय शक्ति की दूसरी विशेषता उसकी सापेक्षता है। जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्ति-सम्बन्धों में परिवर्तन करता है तो उस राष्ट्र के शेष सम्बन्धों में स्वतः परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब हिन्द-चीन ने फ्रांस से और भारत ने ब्रिटेन से स्वतन्त्रता प्राप्त की तो इनके पारस्परिक शक्ति-सम्बन्धों में स्वतः परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार का उदाहरण हम बंगला देश और पाकिस्तान के सन्दर्भ में देखते हैं। सापेक्षता के सम्बन्ध में आर्गेसकी ने लिखा है कि “वाहे दो राष्ट्र मित्र हो अथवा शत्रु केवल सुयोग्य साथी हो या मिलकर लड़ते हों, मिलकर व्यापार करते हो या उनके केवल कुछ समान सांस्कृतिक हित हो, प्रत्येक राष्ट्र यह ध्यान रखता है कि दूसरा क्या कर रहा है तथा जिस क्षण राष्ट्र को यह ध्यान आता है उसी क्षण उसके पास दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है।”¹

तुलनात्मक स्वरूप—राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप सदैव तुलनात्मक पद्धति से आँका जाता है। किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली कहते समय हमारे मस्तिष्क में उन राष्ट्रों का चित्र रहता है जो अपेक्षाकृत निर्बल होते हैं। इसी तरह किसी राष्ट्र को निर्बल कहते समय हम शक्तिशाली राष्ट्रों की तस्वीर से परिचित रहते हैं।

शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र समान नहीं होते—राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से कोई भी दो राष्ट्र समान नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह कि शक्ति की दृष्टि से हम किन्हीं भी दो व्यक्तियों को पूरी तरह समान नहीं पाते। यदि भारत की तुलना चीन, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान या किसी भी अन्य राष्ट्र से करें तो स्पष्ट है कि हम या तो किसी राष्ट्र को भारत से अधिक शक्ति-सम्पन्न पाएँगे या निर्बल। लेकिन यह नहीं हो सकता कि भारत और कोई अन्य राष्ट्र पूरी तरह समान शक्ति-सम्पन्न हों। राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से न्यूनाधिक अन्तर पाया जाएगा।

सभी तत्त्वों का समान महत्त्व—राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्त्वों का समान महत्त्व होता है। राष्ट्रीय शक्ति के किसी एक तत्त्व को अधिक महत्त्व देकर उसके आधार पर यदि एक देश अपनी विदेश-नीति का निर्माण करेगा तो उसे निश्चय ही असफलता प्राप्त होगी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रायः भूगोल की राजनीति (Geo-Politics), राष्ट्रवाद (Nationalism) और सैनिकवाद (Militarism) पर अधिक जोर दिया जाता है जो राष्ट्रीय शक्ति के प्रतिनिधि न होकर उसके केवल एक तत्त्व के परिचायक मात्र हैं।

राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन कठिन है—अन्तिम मुख्य विशेषता यह है कि हम किसी भी राष्ट्र की शक्ति का एकदम सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। कोई भी देश दूसरे देश की शक्ति को सही रूप में कभी नहीं आँक सनता। प्रायः यह

प्रवृत्ति देखी गई है कि लोकतान्त्रिक देश सामान्यतः दूसरे देशों की शक्ति को अधिक और सर्वाधिकारवादी देश दूसरे की शक्ति को कम करके आँकते हैं। एक राष्ट्र स्वयं अपनी ही शक्ति का समुचित मूल्यांकन नहीं कर पाता तो दूसरे राष्ट्रों का क्या कर पाएगा। अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन अवश्य ही किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति का एक साधन सिद्ध होता है जबकि अपनी शक्ति का गलत मूल्यांकन उसके लिए सदैव विफलता और कमजोरी का कारण सिद्ध होगा। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान सदैव अपनी शक्ति का गलत मूल्यांकन करता रहा है जिसका परिणाम विश्व के सामने है। इजराइल के विरुद्ध अरब-राष्ट्रों ने अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन न कर पाने के कड़े फल भोगे हैं।

कुछ विद्वानों के मतानुसार एक देश के व्यवहार, रहन-सहन, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर दूसरे देशों का जो प्रभाव पड़ता है, वह भी शक्ति का एक रूप माना जाएगा, क्योंकि शक्ति आवश्यक रूप से सदैव अपने आपको हिंसात्मक रूप में ही प्रकट नहीं करती। वह शान्तिपूर्ण तरीके से प्रभावी हो सकती है। आज के युग में विश्व-जनमत (World Opinion) का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भारी प्रभाव होता जा रहा है। अनेक देशों को अपनी विदेश-नीति से सम्बन्धित निर्णय केवल विश्व-जनमत के कारण ही बदलने पड़े हैं। विश्व-जनमत को बनाने के लिए प्रत्येक देश प्रचार-साधनों का समुचित विकास करता है ताकि विश्व के अन्य देश भी उसकी नीतियों का समर्थन कर सकें। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आज विश्व-जनमत को भी शक्ति के रूप में उतना ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है जितना सैनिक शक्ति को। यथार्थ में शक्ति एक अविभाजित इकाई है जिसे व्यावहारिक रूप से कभी विभाजित नहीं किया जा सकता।

शक्ति-राजनीति इस तथ्य को मान कर चलती है कि आज राज्यों के आपसी सम्बन्ध अराजकतापूर्ण हैं। इसके मुख्य रूप से तीन कारण हैं—प्रथम, राज्यों की तथाकथित सम्प्रभु स्वतन्त्रता; दूसरे, उच्च सत्ता का प्रभाव; और तीसरे, बाहरी अवरोधों से स्वतन्त्रता।¹ इस अराजकता की स्थिति में एक देश अपने शत्रु के बराबर शक्ति प्राप्त करने मात्र से ही सुरक्षित नहीं बन जाता, वह केवल तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि वह उससे कुछ अधिक शक्तिशाली हो। निरन्तर शक्ति-प्राप्ति का प्रयास ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वास्तविकता है। राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता की शक्ति भी एक ऐसा तत्त्व है जिसे राज्य-व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत अध्ययन में हम राष्ट्रीय शक्ति के सामान्य रूप, इसकी आवश्यकता, इसके आधार तथा इससे सम्बन्धित यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विचारधारा का अवलोकन करेंगे।

राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप

(The Nature of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति का विश्व-राजनीति के क्षेत्र में जितना महत्त्व एवं प्रभाव है

उसे देखते हुए इस विषय पर किए जाने वाले बौद्धिक विचार-विमर्श का परिणाम नगण्य है। 'शक्ति' को राजनीति का एक मूल तत्त्व माना जाता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है और संघर्ष करने के लिए शक्ति प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक काल में तथा प्रत्येक स्थान पर चलती रही है। यह एक ऐसा तथ्य है जो अनुभव पर आधारित है और जिसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि शक्ति के बिना राजनीति का अस्तित्व ही नहीं होता। जिस प्रकार डार्विन ने जीव-विकास में अस्तित्व के लिए संघर्ष (Struggle for Existence) एवं योग्यतम को उत्तरजीविता (Survival of the Fittest) के नियमों का प्रतिपादन किया है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक विश्व-राजनीति के विकास में भी इन नियमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। डार्विन के विकास की प्रक्रिया की इकाई जीव था जबकि इन विचारकों के अध्ययन में विकास की इकाई राज्य है। यह कहा जाता है कि राज्य शक्ति के लिए संघर्ष में केवल इसलिए उलभते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि अनेक देशों द्वारा क्षेत्रीय प्रसार एवं युद्ध की जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं उनके पीछे भी सुरक्षा की भावना प्रेरक के रूप में कार्य करती है। वैसे राइनहोल्ड नीबूर (Reinhold Niebuhr) की तो यह मान्यता है कि जीने की इच्छा और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा के बीच अन्तर नहीं किया जा सकता।¹ एक देश किसी व्यवहार विशेष के समय अपने अस्तित्व की आकांक्षा से प्रेरित हुआ है अथवा शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा से यह निर्णय करना कई बार असम्भव हो जाता है। प्रत्येक राज्य का यह अधिकार होता है कि वह शक्ति प्राप्त करे क्योंकि इसके बिना वह अपने नागरिकों की रक्षा एवं विकास के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता। शक्ति का दुरुपयोग भी किया जा सकता है और किया जाता है, किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि एक राज्य को शक्ति-प्राप्ति का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। दूसरे राज्य द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावनाएँ एक राज्य के शक्ति प्राप्त करने के अधिकार को और भी अधिक आवश्यक बना देती हैं।

राष्ट्रीय शक्ति का आधार सम्प्रभुता की मान्यता को माना जाता है। जब राज्य अपने नागरिकों के विकास का उत्तरदायित्व सम्भाल लेता है तो वह इस दायित्व की पूर्ति के लिए अपनाई गई नीतियों पर किसी भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं चाहता। सम्प्रभुता की मान्यता राज्य को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की ओर प्रेरित करती है, और यह चुनौती भी देती है कि यदि उसने शक्ति-प्राप्ति के प्रयासों में ढील की तो उसका स्वयं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। शक्ति को सम्प्रभुता का एक आवश्यक तत्त्व माना जाता है और कोई भी राज्य सम्प्रभुता के बिना नहीं रह सकता; इसलिए स्वाभाविक है कि कोई भी राज्य शक्ति के बिना भी नहीं रह सकता। राष्ट्रीय शक्ति को सम्प्रभुता की मान्यता द्वारा एक पानूनी औचित्य

प्रदान किया जाना है, दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की यथार्थताएँ भी इसे अपरिहार्य तत्त्व बना देती हैं।

राष्ट्रीय शक्ति की तुलना किसी भी अन्य संस्था या व्यक्ति की शक्ति से नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि राज्य की शक्ति पर कोई भी सैद्धान्तिक सीमा नहीं होती। राज्य के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यावसायिक आदि संस्थाओं के पीछे भी कुछ शक्ति है, किन्तु इनमें से प्रत्येक संस्था की शक्तियों पर सीमाएँ तथा प्रतिबन्ध हैं जबकि राज्य की दमनकारी शक्ति पर कोई मर्यादा नहीं होती। इस अर्थ में राज्य अपने प्रकार की एक अलग ही संस्था है तथा राष्ट्रीय शक्ति इसकी प्राणवायु है। राज्य द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के परिणामस्वरूप उसकी शक्तियों पर अन्य किसी राज्य की शक्ति की मर्यादाएँ भी प्रभावी नहीं हो सकती। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि जब एक राज्य के पाम सैनिक शक्ति की मात्रा कम होती है तो उसकी शक्तियों को अधिक सैनिक शक्ति वाले राज्य द्वारा सीमित किया जाता है।

इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के कानूनी एवं नैतिक दो आधार बन जाते हैं। कानूनी आधार सम्प्रभुता की मान्यता द्वारा प्रतिपादित किया जाता है और नैतिक आधार राज्य के उस उत्तरदायित्व से प्रकट होता है जिसके अनुसार वह अपने नागरिकों के अर्द्ध जीवन की प्राप्ति में सहायता करता है। राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त करने एवं उसमें अधिक से अधिक वृद्धि के लिए किए जाने वाले राज्य के प्रयासों का पहला कारण यह है कि वर्तमान राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था में शक्ति ही सुरक्षा का एकमात्र साधन है। इसका दूसरा कारण शक्ति का आकर्षक रूप है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शान्तिवादी बर्ट्रेण्ड रसल (Bertrand Russel) का कहना है कि यदि सम्भव हो तो प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि वह ईश्वर बन जाए। कुछ लोग तो इस वान को असम्भव मानने से भी इकार करते हैं अर्थात् वे सचमुच ही ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं तथा उनका यह विश्वास रहता है कि वे इस प्रयास में सफल हो जाएंगे। शक्ति-राजनीति का यह एक रोचक पहलू है कि जब भी किसी देश से यह पूछा जाता है कि वह अपनी शक्ति को क्यों बढ़ा रहा है तो वह हमेशा यही जवाब देता है कि विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए वह ऐसा कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में यह बात भारत, पाकिस्तान और साम्यवादी चीन के उदाहरणों में देखी जा सकती है। चीन व पाकिस्तान की सैनिक तैयारियाँ देख कर भारत को अपनी सुरक्षा खतरे में दिखाई देती है, अतः वह भी सैनिक तैयारियाँ करता है। भारत की सैनिक तैयारी में पाकिस्तान व चीन को असुरक्षा की अनुभूति होती है और इसलिए वे अपने प्रयासों की गति को और भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार शस्त्रों की होड़ लग जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रायः ऐसा होता रहता है। शस्त्रों की होड़ के अतिरिक्त मानसिक, नैतिक एवं क्षेत्रीय आधार पर मनमुटाव, तनाव और खिचाव बढ़ना है। इसकी निरन्तर वृद्धि होती रहती है और एक दिन युद्ध का रूप धारण कर लेनी है। यह शक्ति-राजनीति का एक स्पष्ट तथ्य है।

राष्ट्रीय शक्ति के अनेक रूप होते हैं। ई. एच. कार ने इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया है—सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति तथा मत-शक्ति (Opinion)। शक्ति-प्रदर्शन के इन रूपों के अतिरिक्त हत्या एवं आतंक आदि राजनीतिक युद्ध के कुछ रूपों का भी उल्लेख किया जा सकता है। सैनिक शक्ति का महत्व इसलिए है क्योंकि वह एक अन्तिम साधन है। जब एक राज्य शक्ति के अन्य रूपों के प्रयोग द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह युद्ध का सहारा लेता है। यह एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग बहुत कम तथा मजबूरी की अवस्था में ही किया जाता है। कार का कहना है कि शक्ति के क्षेत्र में राज्य का प्रत्येक कार्य युद्ध की दिशा में संचालित होता है, किन्तु यह युद्ध को एक वांछनीय हथियार नहीं मानता अपितु एक ऐसा हथियार मानता है जिसका प्रयोग यह अन्य कोई उपाय शेष न रहने पर ही करता है।

‘राष्ट्रीय शक्ति’ मूल रूप से सैनिक शक्ति ही है, किन्तु इस शक्ति की रचना में अनेक तत्त्व कार्य करते हैं और इसलिए वे भी शक्ति के प्रतीक कहे जा सकते हैं। कई बार ये प्रतीक ही राज्य के लक्ष्य की पूर्ति में सफल हो जाते हैं और युद्ध का मार्ग नहीं अपनाता होता। उदाहरण के लिए, हम एक देश की आर्थिक शक्ति को ले सकते हैं। सैनिक शक्ति के प्रसार के लिए इसका होना परम आवश्यक है। यह कहा जाता है कि युद्धों के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति है। इस कथन में चाहे अतिशयोक्ति हो, किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि करोड़ों रुपये प्रतिदिन का भार डालने वाले युद्ध में कोई भी देश उस समय तक प्रवृत्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके आर्थिक साधन मजबूत न हों। लोकमत पर प्रभाव की शक्ति प्रचार के माध्यम से सम्भव होती है। प्रचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मनोबल की स्थापना का प्रयास किया जाता है और विदेशों में इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रचार को भी राष्ट्रीय शक्ति के अन्य रूपों से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देश में उत्पादन बढ़ाने तथा बलिदान करने की तत्परता पर जोर देता है तथा विदेशों में मैत्री बढ़ाने तथा दुश्मनों को कम करने का प्रयास करता है।

वूटनीति को भी राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप माना जाता है। अधिकांश लेखकों के कथनानुसार यह राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत एवं रूप दोनों हैं।

शक्ति के लिए संघर्ष के आधार

(The Basis of Struggle for Power)

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति का संघर्ष प्रकारण ही नहीं होता, उसके कुछ आधार होते हैं। इस संघर्ष के प्रथम आधार की प्रकृति मानवीय है। इसके अनुसार किसी भी देश की सुरक्षा और एकता अथवा जीवन की एक शर्त होनी है। यदि उस देश की स्वतन्त्रता के लिए कोई धमकी दी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि उसके जीने के तरीके तथा उसके मूल्यों को धमकी दी जा रही है। अतः राज्य का यह मुख्य वस्तुत्व माना जाता है कि वह अपने नागरिकों को शान्ति का वातावरण एवं

सम्पन्नता के धनस्रोत प्रदान करे। राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संघर्ष का एक प्रमुख कारण है, किन्तु यही एकमात्र कारण नहीं है। समुक्तराज्य प्रभारका घोर सोवियत रूस के बीच अपने-अपने प्रश्नों पर मतभेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक एवं राजनीतिक संगठनों तथा विश्वासों के बीच स्थित भिन्नताएँ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के मुख्य कारण हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि विचारधारा (Ideology) कभी-कभी तो राष्ट्रीयता की भावना से भी ऊपर उठ जाती है। एक देश के लोग दूसरे देश का समर्थन केवल इसी बात के आधार पर करने लगते हैं कि वहाँ के लोगों के विचार तथा विश्वास उनकी के जैसे हैं। विचारधारा के आधार पर ही विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत जो संघर्ष या गृह-युद्ध प्रारम्भ होते हैं वे बढ़कर अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप धारण कर लेते हैं। इस दृष्टि से द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद प्रारम्भ होने वाला ग्रीन-युद्ध दो नैतिक दर्शनों के मध्य छिड़ने वाला एक विवाद था। मॉन्टेवी महाशय इस मत के समर्थक नहीं हैं। उनका कहना है कि राज्य जो भी कार्य करता है या जो भी निर्णय लेता है उसका मुख्य उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। वह विचारधाराओं के आधार पर तो अपने व्यवहार एवं निर्णयों का औचित्य मान्य सिद्ध करता है। अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का एक तीसरा आधार मूल्यों को माना जाता है। क्लाइड क्लुक्होर्न (Clyde Kluckhohn) आदि जाति-शास्त्र के विद्वानों का मत है कि संघर्षपूर्ण नैतिक मूल्य मनमुटाव के प्रधान कारण होते हैं। मूल्यों के द्वारा व्यवहार को प्रभावित किया जाता है और कभी-कभी तो उस पर निर्णय भी किया जाता है।

विचारधारा एवं विश्वास के आधार पर मनुष्य की बौद्धिक एवं मनोऽज्ञानिक आवश्यकताओं को बल दिया जाता है। इससे यह बात हो जाता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है तथा वह जो कुछ कर रहा है वह ठीक है अथवा नहीं। मूल्य-व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य होता है एक ऐसी चीज को चुनौती देना जो मानव-जाति के लिए गम्भीर अर्थ रखती है। इस प्रकार का व्यवहार नैतिक सुरक्षा एवं निश्चिन्ता को छतरे में डाल देता है। एक देश की विदेश-नीति पर वहाँ के लोगों के सामाजिक मूल्यों का पर्याप्त प्रभाव रहता है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि नैतिक एवं सैद्धान्तिक विश्वासों के प्रतिरित्त लोगों का या राज्य का कोई अन्य हित नहीं होता। अपने स्वीकृत नैतिक विचारों के दृष्टिकोण से ही वे यह तथ्य करते हैं कि उनके हित क्या हैं।¹ विदेश-नीति के सम्बन्ध में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। जब एक देश यह मान लेता है कि पूँजीवादी व्यवस्था का अप्रतिहार्य गति के कारण संघर्ष अनिवार्य है, तब वह यह नीति अपनाता है कि गैर-साम्यवादी देशों की वयाशक्तिन सहायता करे ताकि वे वयास्यदित को बनाए रखें और शान्ति का विरोध करें। तैाान्तिक मूल्यों को विदेश-नीति का अन्तिम निर्णायक माना जाए अथवा नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अधिकांश विचारकों के बीच मतभेद है। ऐसे अधिक विचारक यही मानते हैं कि कोई भी राजनीतिज्ञ उन मूल्यों की अवहेलना

नहीं कर सकता जो उसके बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा मान्य हैं। दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कोई भी ऐसी विचारधारा यथार्थवादी नहीं कही जा सकती जो विरोधी मूल्यों पर गम्भीर रूप से विचार करने में असमर्थ हो।

कोई भी देश जब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार को प्रभावित करने में उक्त तत्वों के अतिरिक्त समाज के दबाव-समूह भी पर्याप्त महत्त्व रखते हैं। एक देश में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों एवं बुद्धिजीवी वर्गों के अलग-अलग आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थ होते हैं और उसी के अनुरूप वे देश की विदेश नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनकी स्वामिभक्ति उनके देश की अपेक्षा उनके धार्मिक, व्यावसायिक अथवा ऐसे ही अन्य संगठनों के प्रति अधिक रहती है। जब ये लोग अपने देश की विदेश-नीति के लक्ष्यों का मूल्यांकन करने लगते हैं तो उनका दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का होता है।

लेनिन ने राज्यों के व्यवहार एवं शक्ति-संघर्ष के लिए एक अन्य आधार को उत्तरदायी ठहराया है। उनका कहना है कि 'साम्राज्यवाद' पूँजीवाद का दूसरा सोपान है। पूँजीवादी देश अपने अतिरिक्त उत्पादन के लिए सुरक्षित बाजार चाहते हैं। अपने देश में उनको यह प्राप्त नहीं हो पाता। लेनिन की व्याख्या चाहे वैज्ञानिक हो अथवा न हो, किन्तु इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक औद्योगिक एवं बैंक-संस्थाओं को देश की राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण करना होता है। लेनिन ने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग या वर्ग होते हैं जो दूसरे लोगों की जमीन, जीवन एवं भूमि पर अपनी राष्ट्रीय सत्ता का प्रसार करना चाहते हैं।

शक्ति-संघर्ष के रूप

(The Forms of Struggle for Power)

मॉर्गेंथौ (Morgenthau) ने शक्ति-संघर्ष के तीन मुख्य रूपों का वर्णन किया है। ये रूप शक्ति सम्बन्धी विशेष दृष्टिकोण से प्रभावित रहते हैं। शक्ति के ये तीन मूल रूप निम्न प्रकार हैं—

1. शक्ति को कायम रखना (To Keep Power)—शक्ति का यह वह रूप (Pattern) है जिसमें एक देश शक्ति-स्थिति को यथावत् रखना चाहता है। शक्ति के इस रूप से प्रभावित विदेश-नीति का प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि विश्व के देशों की शक्ति-स्थिति इस समय जैसी है वह वैसी ही रहे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। यह नीति यथास्थिति (Statusquo) की नीति कही जाती है।

2. शक्ति में अभिवृद्धि (To Increase Power)—कुछ देशों की विदेश-नीति का लक्ष्य वर्तमान शक्ति-स्थिति को पलटना होता है। ऐसे देशों के पास जितनी शक्ति होती है वे उसमें और भी अधिक वृद्धि करना चाहते हैं। शक्ति-स्थिति में वे देश ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो उनके पक्ष में हो। ऐसे देश साम्राज्यवाद की नीति का संपोषण करते हैं।

3. शक्ति का प्रदर्शन (To Demonstrate Power)—बहुत से देश ऐसी नीति अपनाते हैं जिनके अनुसार उनको शक्ति का प्रदर्शन करने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। यह प्रदर्शन शक्ति को यथावत् रखने तथा उसे बढ़ाने या इन दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इस नीति की प्रतिष्ठा-नीति कहते हैं।

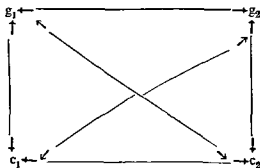
उक्त तीनों ही रूपों में शक्ति के विभिन्न खेल समय-समय पर खेले जाते हैं तथा ये ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नियमित करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् का शक्ति-सर्प हमें डाविन के अस्तित्व के लिए संघर्ष (Struggle for Existence) तथा योग्यतम का उत्तरजीवन आदि सिद्धान्तों का स्मरण कराता है जिनका उल्लेख जीवन विकास के प्रसंग में किया जा चुका है, किन्तु यह राज्य-व्यवस्था के विकास पर पूरी तरह लागू होता है जब विश्व के राज्यों के हित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं सैनिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर टकराते हैं तो एक संघर्ष की सी स्थिति पैदा हो जाती है। इस संघर्ष में जो राष्ट्र विजयी होता है वह आगे बढ़ जाता है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसको सम्माननीय पद प्राप्त हो जाता है। इस पद की प्राप्ति के लिए प्रायः सभी राष्ट्र समान रूप से तालाशित रहते हैं।

क्रियाशील राष्ट्रीय शक्ति—स्प्रौट एवं स्प्रौट के विचार¹

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति (पावर) को बहुधा 'सैनिक शक्ति' के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति के सन्दर्भ में स्प्रौट एवं स्प्रौट ने लिखा है—“यह जोर देकर कहना पड़ेगा कि अमेरिकी प्रयोग में पावर शब्द बहुधा सैनिक शक्ति का बोध कराने का प्रयत्न करता है या कम से कम बल-प्रयोग या उसकी घमकी का बोध कराता है जो सैनिक शक्ति का सार है।” लेखक द्वय का मन है कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक तत्त्व पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने का एक तरीका यह है कि राज्यों की परस्पर क्रियाओं को अधिक सायंक शब्दों में व्यक्त किया जाए।” इसे यानो क्रियाशील राष्ट्रीय शक्ति को स्पष्ट समझ पाने के लिए लेखक महोदयों ने एक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अत्यधिक सरलीकृत मॉडल पर विचार किया है। तदनुसार (मंशेष में)—

इस मॉडल में केवल दो राज्य हैं—राज्य 1 और राज्य 2। प्रत्येक राज्य में क्रिया के दो स्तर हैं—सरकार (g से अभिहित) अर्थात् एक संगठन जो राज्य के नाम पर कदम उठाने का अधिकारी है तथा जन-क्षेत्र (c से अभिहित) जिसमें वे सभी लोग सम्मिलित हैं जो कानूनन सरकारी सत्ता के अधीन हैं। इन अनिसरलीकृत दो राज्यों की व्यवस्था में यह कल्पना की जा सकती है कि सन्देश दुनुरफा विभिन्न धाराओं में अवलिखित रीति से चलेंगे—

1 Sprout and Sprout : op. cit., pp. 190-211.



G_1-C_1 और G_2-C_2 धाराएँ सरकार और उमकी जनता के बीच एक राष्ट्रीय समुदाय के अन्तर्गत सन्देश बहान करती हैं। इस धारा में सन्देश होंगे—कानून, विशेष आदेश, घोषणाएँ, सार्वजनिक सम्बोधन, प्रेस-विज्ञप्ति और सरकार से जनता के नाम प्रसारित अन्य सन्देश। इसी धारा में माँगें, अपीलें, सरकारी नीतियों की आलोचनाएँ, थोटा अर्थात् जनता से सरकार के नाम सन्देश प्रवाहित होते हैं। एक विरादरी के भीतर सरकार-जनता धारा में बहने वाले कार्य-व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की हमारी परिभाषा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कार्य-व्यापार नहीं हैं। फिर भी वे राज्य के सरकारी नियंत्रणकर्ताओं (अर्थात् सरकार) के पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण पक्षों का निर्माण कर सकते हैं।

धारा C_1-C_2 विभिन्न राज्यों में स्थित व्यक्तियों या गुटों के बीच सभी गैर-सरकारी सन्देशों का बहान करती है। इस धारा में—गैर-सरकारी खत, तार, टेलीफोन वार्ताएँ और रेडियो प्रसारण, पर्यटकों, छात्रों और अन्य विदेशियों के स्थानीय जनता से सम्पर्क सम्मिलित हैं। अखबार, पत्रिका, पुस्तक और अन्य गैर-सरकारी मुद्रित सामग्री जो देश में बाहर से आती है, अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य और वित्त का वह अंश जिसका संचालन गैर-सरकारी तौर पर होता है, और कई अन्य प्रकार के गैर-सरकारी कार्य-व्यापार भी इसी के अन्तर्गत शामिल होते हैं। ये कार्य-व्यापार अवश्य ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की सामान्य कोटि में आ जाते हैं। ये अन्तर्राष्ट्रीय-राजनीतिक सम्बन्धों के लिए अर्थात् उन सम्बन्धों के लिए जिनमें संगठित राष्ट्रीय विरादरियों के बीच उद्देश्य या स्वार्थ का कुछ सघर्ष हो, बहुत महत्वपूर्ण हो या न हो, किन्तु सभी राज्यों में खास तौर पर कम्युनिस्ट तथा अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में, यह सदा कठिन, कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय कार्य-व्यापारों में सरकारी-गैरसरकारी का स्पष्ट अन्तर अग्रमम्भ होता है अर्थात् यह तय करना कठिन होता है कि विनिष्ट कार्य-व्यापार को C_1-C_2 कोटि में माना जाए या G_1-C_2 अथवा G_2-C_1 में।

G_1-C_2 और G_2-C_1 धाराएँ सन्देशों का बहान मुख्यतः एक ही दिशा में करती हैं—सरकार से किसी विदेशी जनता की ओर। कुछ सन्देश विपरीत दिशा में भी जाते हैं—उदाहरणार्थ गैर-सरकारी बैंकों द्वारा विदेशी सरकारों को ऋण या अधिक

स्पष्ट रूप में फारस की खाड़ी के चारों ओर अरब-राज्यों के लिए अमेरिकी तेज कम्पनियों के व्यापारिक कार्यक्रम। कुछ राज्यों में, खासकर अमेरिका में, गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा विदेशी सरकारों से राजनीतिक समझौते प्रबंध माने जाते हैं। दूसरे ओर यह चिरपरिचित तथ्य है कि एक सरकार दूसरी सरकारों पर उनकी जनता के बीच धुआंधार प्रचार द्वारा असर डालने की कोशिश करती है। E_1-C_2 और E_2-C_2 ही वे धाराएँ हैं जिनमें होकर दूसरे राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को उलटने वाले कार्य-व्यापार चलते हैं और उन्हीं धाराओं में वास्तविक या शीतयुद्ध के कार्य-व्यापारों में से अनेकों का प्रवाह होता है।

धारा E_1-E_3 सरकारों के बीच सभी सन्देशों के विनिमय की धारा है। यह कूटनीति तथा अन्य सरकारों के बीच होने वाले कार्य-व्यापारों का ही वहन करती है।

राष्ट्रान्तरीय क्रियाओं की पान्त्रिकताओं, पद्धतियों, लक्ष्यों और प्रभावों की रूपरेखा में इन चार प्रकार की धाराओं को ध्यान में रखना लाभप्रद होगा और इस तरीके से शक्ति के सामान्य सम्प्रत्यय में परिणत किया जा सकेगा।

राज्यशिल्प के यन्त्रों से अभिप्राय है केवल वह मानवीय या अमानवीय तन्त्र, जिसका उपयोग राजनेता अन्य राष्ट्रों के व्यवहार को अभीष्ट ढंग से प्रभावित करने के लिए करते हैं। इस तन्त्र की प्रकृति और क्षेत्र नीचे की रूपरेखा से स्पष्ट होंगे—

1. अमानवीय यन्त्र, जिनमें शामिल हैं—

- (अ) संचार की यन्त्र-सज्जा
- (ब) औचित्यवादी विचार
- (स) प्राविधिक जानकारी
- (द) दबाव और ध्वंस की यन्त्र-सज्जा
- (य) अन्य वस्तुएँ—साक्ष-सामग्री, कच्चा माल, पूंजीगत सामान, सामग्री आदि।

2. मानवीय यन्त्र, जिनमें शामिल हैं—

- (अ) सरकारी एजेंसी और कर्मचारी—कूटनीतिक, सैनिक जनसम्पर्क और कई अन्य।
- (ब) गैर-सरकारी एजेंसी और व्यक्ति—बैंक और बीमा व्यवसाय के कर्मचारी, शिक्षक, इंजीनियर, पत्रकार और कई अन्य।

व्यवहार में, राज्य-शिल्प के गैरीमानवीय यन्त्र मानव द्वारा ही क्रियाशील होते हैं। संवाद-प्रेषण-यन्त्र तभी कार्य करता है जब कोई उसका उपयोग करे। यही बात औचित्यवादी विचारों, प्राविधिक ज्ञान, सैनिक सज्जा और गैर-सैनिक वस्तुओं और सेवाओं के बारे में भी है।

यही पर यन्त्रों और पद्धतियों के बीच अन्तर का प्रश्न उपस्थित होता है। 'पद्धति' शब्द से हमारा अभिप्राय है विभिन्न यन्त्रों या उनके समूहों द्वारा किए जाने वाले कार्य। इस प्रकार, उदाहरणार्थ, विदेश-कार्पोरेशन और राजदूतावास, अपने कर्मचारियों समेत राज्य-शिल्प के यन्त्र हैं, लेकिन कूटनीति एक पद्धति है। सैनिक, प्रायुध और उन्हे चलाने वाले सैनिक, यन्त्र हैं, विविध प्रकार की सैनिक गतिविधियाँ पद्धति

हैं। एक लोकतन्त्रीय देश में स्थित कम्यूनिस्ट पार्टी किसी विदेशी कम्यूनिस्ट सरकार का यन्त्र हो सकती है; उस दल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली ध्वंस-क्रियाएँ पद्धति है। इंजीनियर, फार्म-विशेषज्ञ, अन्य विशेषज्ञ यन्त्र हो सकते हैं, प्राविधिक सहायता पद्धति है। विविध प्रकार की आर्थिक सामग्रियाँ यन्त्र हो सकती हैं, विदेशी राष्ट्रीयों द्वारा उपहार और ऋण पद्धति है।

राज्य-शिल्प की पद्धतियों का वर्गीकरण कई तरीकों से किया जा सकता है—प्रयुक्त यन्त्रों के अनुसार, क्रिया के लक्ष्य के अनुसार, अभीष्ट प्रभावों के अनुसार या वस्तुतः उपलब्ध प्रभावों के अनुसार। निम्नांकित विश्लेषण काम में आने वाले यन्त्रों के अनुसार है—

1. पद्धतियाँ—प्रथमतः संचार के यन्त्रों से सम्बन्धित—

(अ) समझौता वार्ता—कूटनीतिक सम्मेलन आदि।

(ब) नीति की एकतरफा घोषणा।

(स) जन-सम्पर्क—जो ख स नीतियों से साफ-साफ सम्बन्धित न हो।

(द) मनोवैज्ञानिक आक्रमण—तोड़-फोड़, मनोबल पर आघात।

2. पद्धतियाँ—प्रथमतः औचित्यवादी विचारों और/या प्राविधिक ज्ञान से सम्बन्धित—

(अ) सामाजिक उपलब्धियों का प्रदर्शन—वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग प्रदर्शन, निर्देशित पर्यटन, प्रदर्शनियाँ, मेले आदि।

(ब) सैनिक विकास में सहायता।

(स) अन्य प्राविधिक सहायता कार्य।

3. पद्धतियाँ—प्रथमतः गैर-सैनिक वस्तुओं और सेवाओं की सुविधाओं से सम्बन्धित—

(अ) वस्तुओं और सेवाओं का दान—उपहार, ऋण आदि।

(ब) वस्तुओं और सेवाओं को देने से इकार—बहिष्कार, नाकेबन्दी आदि।

(स) अन्य प्रकार की आर्थिक कार्यवाही।

4. पद्धतियाँ—प्रथमतः दबाव और ध्वंस के यन्त्रों से सम्बन्धित—

(अ) तोड़-फोड़।

(ब) आतंक—आयुध प्रदर्शन, सैनिक कार्यवाही की धमकी आदि।

(स) सीमित सैनिक गतिविधियाँ—सैनिक हस्तक्षेप, सीमित युद्ध आदि।

(द) असीमित सैनिक गतिविधियाँ—पूर्ण-युद्ध आदि।

पूर्व पृष्ठों में कई स्थलों पर लक्ष्य-राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है और उस राज्य की सरकार और जनता का त्रिधा के विशिष्ट लक्ष्य के रूप में उल्लेख किया है। लक्ष्य का अर्थ है वह व्यक्ति, व्यक्ति-समूह या भौतिक वस्तुएँ जिनकी ओर विभिन्न पद्धतियों का निर्देश होना हो। ध्वंसात्मक सैनिक अर्थ का लक्ष्य हममें शामिल है। लेकिन लक्ष्य का राजनीतिक संप्रत्यय उसके अलावा बहुत कुछ अपनी

परिधि में समाविष्ट कर लेता है। यह शब्द क्रियाशील राज्य की माँगों के प्रति सक्रिय या निहिन विरोध का निश्चित भाव लिए है, लेकिन उसके साथ युद्ध या शत्रुता का होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार ब्रिटेन, उन राज्यों में से एक है, जिनके साथ अमेरिका की निकटतम एकरूपता है और जो बार-बार अमेरिकी क्रिया का एक लक्ष्य बनता है, लेकिन किसी कल्पनाजन्य परिस्थिति में सम्भावित शत्रु के रूप में उसका सम्प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। संक्षेप में क्रिया-लक्ष्य का सम्प्रत्यक्ष स्वतः, सम्भावित, द्वेष या शत्रुता का भाव व्यक्त नहीं करता, केवल कुछ अंग में विरोध या प्रतिरोध व्यक्त करता है जिसे उक्त क्रिया पार करने वाली होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विशिष्ट क्रिया-लक्ष्यों में निम्नांकित शामिल हैं—

1. लक्ष्य-राज्य के सरकारी निर्णायकर्ता।
2. लक्ष्य-राज्य के भीतर अन्य प्रबुद्ध गुट।
3. लक्ष्य-राज्य की पूरी जनसंख्या।
4. लक्ष्य-राज्य का भौतिक भू-भाग।
5. लक्ष्य-राज्य के भू-भाग पर मानव-निर्मित प्रतिरूप।

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि क्रिया का उद्देश्य उनके व्यवहार की अभीष्ट दिशाओं में प्रभावित करना है जो लक्ष्य-राज्य पर शासन करने हैं और अन्य सरकारों से साधिकार व्यवहार करते हैं। इस परिणाम के लिए समझाने या दबाव डालने की क्रिया सीधे राज्य-प्रमुख, विदेश मंत्री या लक्ष्य-राज्य के अन्य साधिकार प्रबन्ध पर लागू की जानी चाहिए। लेकिन उन पर समझाने या दबाव डालने की क्रिया अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। प्रभावशाली गुटों या पूरे राजनीतिक क्षेत्र की राय या मन:स्थिति बदल कर भी वही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है अथवा क्रिया-शील राज्य अपनी माँगें थोपने के लिए उनके नगरों या अन्य निर्माण कार्य का ध्वंस करने या लक्ष्य-राज्य के भू-भाग पर कब्जा करने का भी प्रयास करता है।

चाहे जो भी पद्धति या पथ अपनाएँ, सरकारें अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही कदम उठाती हैं। सरकारी अफसर, राजनीतिज्ञ और उनकी जनता आमतौर पर अपनी माँगों को, आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा के औचित्य का जामा पहना देती हैं। शायद उतनी ही दृढ़ता से उनके विरोधी उन्हीं माँगों के लिए आक्रमणकारी हरादों के आरोप लगाते हैं। हमने पहले ही उम कठिनाई को देख लिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति में किसी राज्य की, विशेषकर अपने राज्य की विदेश-नीति के उद्देश्यों का आवेश-रहित मूल्यांकन करने में आती है, फिर भी यह काम कठिन और शायद अधिक कष्टप्रद होगा यदि क्षण भर के लिए राज्यों की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न प्रभावों पर उनकी तह में द्विपी नीयत और उद्देश्य की परवाह न कर ध्यान केन्द्रित किया जाए।

ऐसे प्रभावों का स्थूल वर्गीकरण विशिष्ट नीतिपरक और विशिष्ट नीति-रहित हो सकता है। विशिष्ट नीतिपरक प्रभाव—यानी विशिष्ट माँगों से सम्बन्धित प्रभाव—में माँगों की मान्यता, परस्पर-विरोधी माँगों के बीच समझौता या माँगों

का तिरस्कार कुछ भी हो सकता है। विशिष्ट नीतिरहित प्रभाव व्यवहारों और वस्तुस्थितियों की पूरी श्रेणी को अपनी परिधि में समेट लेते हैं। हो सकता है माँग करने वाले राज्य के पक्ष या विपक्ष में मनोवैज्ञानिक रुचि का विकास हो अथवा प्रभाव लक्ष्य-राज्य की आर्थिक या सैनिक क्षमताओं को कमजोर करने वाला हो या हो सकता है कि प्रभाव लक्ष्य-राज्य की आर्थिक या सैनिक क्षमताओं को विवश या कमजोर करने वाला हो। यह भी सम्भव है कि प्रभाव लक्ष्य-राज्य की या गैर-सैनिक या दोनों प्रकार की जनता को आतंकित करने का हो, या उसके भू-भाग पर पूर्ण या आंशिक कब्जे का हो या उसकी जनसंख्या और भौतिक निर्माण के कुछ भाग का विनाश हो या उसे निरन्तर चिन्ताप्रद समझ कर उस राज्य का पूर्ण अथवा आंशिक विनाश हो।

अप्रतिष्ठित सारणी में कुछ पैमानों के विन्यास दिए जा रहे हैं जिनके क्रिया-विन्यास के प्रोक्षित अम्ली प्रभाव स्थिर किए जाने चाहिए। विभिन्न प्रेक्षकों के बीच खास क्रियाओं के प्रभावों के बारे में मतभेद हो सकता है। लेकिन प्रेक्षण और भाष्य में ऐसे अनिवार्य विवरण की गुंजायश छोड़कर भी इन पैमानों पर उठाए गए कदमों के प्रभावों को स्थिर करने के अभ्यास से कई लाभ होने चाहिए। इससे किसी राज्य की विदेश-नीति की तह में छिपी रणनीति को समझने में सहायता मिलनी चाहिए। इससे दी हुई अम्ली स्थिति में उस रणनीति के विभिन्न पक्षों की तुलनात्मक सप्रभावता (या निष्प्रभावता) पर भी प्रकाश पड़ेगा। विशेष रूप से इसके द्वारा दो या अधिक सम्बन्धित राज्यों की सापेक्ष राजनीतिक सामर्थ्य—यानी प्रत्येक की अन्य के व्यवहार को प्रभावित करने की वास्तविक योग्यता—के बारे में निष्कर्ष के लिए आँकड़े मिल जाएँगे। सारणी की राजनीतिक सामर्थ्य और राजनीतिक क्षमताओं के सम्प्रत्ययों के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाला पुल माना जा सकता है।

सारणी में प्रस्तुत विश्लेषण-पद्धति के विस्तार से कई अतिरिक्त काम किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई दो या अधिक राज्यों की रणनीतियों सापेक्ष सप्रभावता की एक-एक कोटि लेकर तुलना की जा सकती है। ऐसा करने पर ये प्रश्न प्रसर हो जाएँगे जैसे—राज्य A की रणनीति राज्य B की तुलना में अधिक (या कम) सप्रभावी क्यों है? मतलब यह है कि A का असर B के (हर प्रकार के) व्यवहार पर, B के A पर असर की तुलना में इतना अधिक (या कम) क्यों है? ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना और उत्तर देने का प्रयास, राज्यों के शक्ति-सम्बन्धों में शक्ति के तथा उसके प्रकट रूपों के अम्ली सम्प्रत्यय की दिशा में राजमार्ग से आगे बढ़ना होगा।

सारणी—क्रियाशील राष्ट्रीय शक्ति

प्रभाव—A की विशिष्ट माँगों का B की सरकार की प्रतिक्रियाओं पर
स्वीकृति..... गमभीता..... निरस्कार.....

प्रभाव—A की जनसम्पर्क क्रियाओं का B की सरकार, अन्य प्रबुद्धवर्ग या पूरी जनता पर
संवेदीपूर्ण..... कोई प्रभाव नहीं..... शत्रुतापूर्ण.....

प्रभाव—A के सर्वविधि कार्यों का B के पूरे समाज की एकता और मनोबल पर
दृढतर..... कोई प्रभाव नहीं..... क्षीणतर.....

प्रभाव—A के कार्यों का B की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता पर
बढ़ी हुई..... कोई प्रभाव नहीं..... घटी हुई.....

प्रभाव—A के अहिंसात्मक कार्यों का B की सैनिक शक्ति की अवस्था पर
दृढतर..... कोई प्रभाव नहीं..... क्षीणतर.....

प्रभाव—A की सैनिक गतिविधि का B की सैनिक शक्ति की अवस्था पर
दृढतर..... कोई प्रभाव नहीं..... क्षीणतर.....

प्रभाव—A की सैनिक गतिविधि का B के भू-भाग की भौतिक स्थिति, जनसंख्या
या निर्माण आदि की दशा पर
सुरक्षित..... कोई प्रभाव नहीं..... ध्वस्त.....



राष्ट्रीय शक्ति का सार और तत्त्व— राष्ट्रीय शक्ति का उद्भव और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय (Essence and Elements of National Power— Evolution of National Power and International Community)

“भौतिक भूगोल विश्व-राजनीति को निरन्तर रूप से अधिक प्रभावित करने वाला तत्त्व है। यह उन आवश्यकताओं, लक्ष्यों, नीतियों एवं शक्तियों को प्रभावित करता है जिनको राज्य अपने हितों की दृष्टि से अपनाते हैं।”

—पेडलफोर्ड तथा लिंकन

राष्ट्रीय शक्ति के कुछ आधारभूत तत्त्व होते हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। इन तत्त्वों में कुछ तो दृश्य हैं जैसे सैनिक-शक्ति और कुछ अदृश्य हैं जैसे विचारधारा, मनोबल आदि। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय शक्ति की परिधियाँ इतनी अस्पष्ट हैं कि हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह नहीं देख सकते। ये सभी तत्त्व किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि शक्ति एक अविभाज्य वस्तु है। इसके पहले कि हम इन विभिन्न तत्त्वों का उल्लेख करें, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि केवल इन तत्त्वों की उपस्थिति मात्र से ही कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन जाता। राष्ट्र के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है कि इन तत्त्वों के अस्तित्व के साथ-साथ राष्ट्र में इनके समुचित उपयोग करने की क्षमता भी हो तभी वह अपने प्रभाव का विस्तार करने में सफल हो सकता है। पुनश्च, यह भी स्मरण रखना होगा कि राज्य आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय आदि अनेक घरातलों पर सम्बन्ध स्थापित करते हैं जिनका शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं होना, लेकिन यदि इन सम्बन्धों का उपयोग भी प्रभाव-विस्तार के उद्देश्य से किया जाए तो हम उन्हें शक्ति से सम्बद्ध मानेंगे।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों का वर्गीकरण और प्रकृति

राष्ट्रीय शक्ति के इन तत्त्वों को माँगिन्यो ने दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रथम वर्ग को वे सापेक्षतया स्थायी तत्त्व (Relatively Stable Elements) कहते हैं और दूसरे वर्ग को अस्थायी तत्त्व अर्थात् निरन्तर परिवर्तित होने वाले तत्त्व

(Elements Subject to Constant Change) कहते हैं। इन दोनों वर्गों में समाविष्ट राष्ट्रीय शक्ति के तत्व मॉर्गेंथो के मतानुसार भी होते हैं जो ये हैं—

1. भूगोल (Geography)
2. प्राकृतिक साधन (Natural Resources)
3. औद्योगिक क्षमता (Industrial Capacity)
4. सैनिक तैयारियाँ (Military Preparedness)
5. जनसंख्या (Population)
6. राष्ट्रीय चरित्र (National Character)
7. राष्ट्रीय मनोबल (National Morale)
8. दूतनीति का गुण (Quality of Diplomacy)
9. सरकार का गुण (The Quality of Government)

पामर तथा पाकिंस ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर-मानवीय एवं मानवीय वर्गों में विभाजित किया है। गैर-मानवीय तत्वों में वे भूगोल तथा प्राकृतिक साधनों को सम्मिलित करते हैं और मानवीय तत्वों में वे निम्नलिखित पाँच का उल्लेख करते हैं—

1. जनसंख्या (Population)
2. तकनीकी ज्ञान (Technology)
3. विचारधाराएँ (Ideologies)
4. मनोबल (Morale)
5. नेतृत्व (Leadership)

राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्णन अन्य अनेक लेखकों द्वारा भी किया गया है। इनमें थोड़ा-बहुत ही भिन्न है। उदाहरण के लिए, श्लीचर ने अन्य तत्वों के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (Productive Capacity) एवं आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं (Economic and Political Institutions) का भी उल्लेख किया है।

मॉर्गेंथो (Morgenthau) की भाँति श्लीचर (Schleicher) भी यह स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में स्थायित्व (Stability) की दृष्टि से अन्तर रहता है। कुछ तत्व दूसरों की प्रवेक्षा अधिक स्थायी होते हैं तथा उनको मापना भी सरल होता है। उदाहरण के लिए, भूगोल तथा प्राकृतिक साधनों में स्थायित्व और मापे जाने की सम्भावनाएँ जनसंख्या की संस्थाओं एवं गुणों की तुलना में अधिक होती हैं। ये सभी तत्व मिलकर एक देश को तीन प्रकार की सामर्थ्य प्रदान करते हैं—

1. आर्थिक सामर्थ्य (Economic Capacity),
2. मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य (Psychological Capacity), तथा
3. भौतिक सामर्थ्य (Physical Capacity)।

राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों का महत्व समय और परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील है। दो सौ वर्ष पूर्व जनसंख्या अथवा भौगोलिक स्थिति का

राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से जो महत्त्व था वह आज के प्रक्षेपास्त्रों और ध्वनि से भी तेज चलने वाले बम-वर्षकों के युग में नहीं है। पुनरुच, यह तथ्य भी स्मरणीय है कि विभिन्न तत्त्वों का योग मात्र ही राज्य की शक्ति का परिचायक नहीं होता। राज्य की शक्ति को यथार्थ रूप में तो हम उसके व्यवहार तथा विभिन्न तत्त्वों के प्रयोग की कला और सामर्थ्य के माध्यम से ही परख सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों का समुचित अध्ययन हमें राज्य की सामर्थ्य का अनुमान लगाने में सहायक होता है, अतः आवश्यक है कि किसी भी राज्य की शक्ति के किसी तत्त्व का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित सामान्य बातों को अवश्य ध्यान में रखें—

प्रथम, शक्ति के सभी तत्त्व सापेक्ष महत्त्व रखते हैं। उनका मूल्यांकन करते समय अन्य राज्यों, विशेषतः पड़ोसी एवं विरोधी राज्यों के ऐसे तत्त्वों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे यदि हम यह कहे कि ग्रेट-ब्रिटेन की जनसंख्या 60 मिलियन (6 करोड़) है तो यह कथन उस समय तक उसके शक्ति-सम्बन्धों की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखता जब तक कि उसके आस-पास के देशों की जनसंख्या को तथा महाशक्तियों की जनसंख्या को न देखा जाए।

दूसरे, राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों की मात्रा का उल्लेख मात्र कर देना भी निरर्थक होगा। हमें यह भी देखना होगा कि 60 मिलियन जनसंख्या में कितने लोग वयस्क हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने बालक हैं, कितने रोगी, अपाहिज तथा असमर्थ हैं? कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या क्या है तथा पुरुषों की संख्या क्या है? इनमें भी शिक्षित लोग कितने हैं और अशिक्षित कितने? आदि-आदि। इन सारी बातों का स्पष्टीकरण करने के बाद ही जनसंख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि एक विशेष देश की राष्ट्रीय शक्ति कितनी है।

तीसरे, राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व अपने आप में कोई महत्त्व नहीं रखते। उनकी उपयोगिता एवं सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि उनके लिए शक्ति के अन्य तत्त्वों का कितना बल प्राप्त है। जब कभी हम एक तत्त्व का मूल्यांकन करेंगे तो इसके लिए दूसरे तत्त्वों की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। यदि शक्ति के अन्य तत्त्वों का एक राज्य में अभाव है तो किसी भी एक तत्त्व की पर्याप्त मात्रा को वहाँ सार्थक नहीं माना जा सकता और इसलिए वह भी महत्त्वहीन बन जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक देश सैनिक तैयारियों की दृष्टि से पर्याप्त आगे है, किन्तु उसके पास पर्याप्त जनसंख्या एवं औद्योगिक स्रोत नहीं हैं तो वह अपने उस शत्रु के सामने नहीं टिक सकेगा चाहे उसकी सैनिक तैयारियाँ उतनी अधिक नहीं थी। इसका कारण यह है कि जब उस देश विशेष को युद्ध में क्षति होगी तो वह उसकी पूर्ति करने में अपने आपको असमर्थ पाएगा। जब एक देश के पास अतिरिक्त साधन होते हैं तो उनका महत्त्व शक्ति की स्थिति की दृष्टि से होता है, किन्तु तत्कालीन स्थिति में उनसे राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि का एक आवश्यक साधन नहीं माना जा सकता। भारतवर्ष एवं साम्यवादी चीन की जनसंख्या एक दृष्टि से उनकी राष्ट्रीय शक्ति को बढाते हैं, किन्तु दूसरी दृष्टि से वे उसकी कमजोरी के कारण हैं क्योंकि

इन देशों के पास इतने साधन-स्रोत नहीं हैं कि वे अपनी जनसंख्या का स्वयमेव हा-
भरण-पोषण कर सकें। सच तो यह है कि जिसे एक स्थिति में शक्ति का तत्त्व माना
जाता है वही दूसरी स्थिति में एक भार बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक
देश अन्य तत्त्वों की दृष्टि से गरीब है, किन्तु उसके प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त सम्पन्न हैं
तो वह देश बड़ी शक्तियों की तलचापी नजरो का शिकार बन जाएगी और अपनी
स्वतन्त्रता खोकर साम्राज्यवादी शक्तियों का उपनिवेश मात्र रह जाएगा।

चौथे, शक्ति के तत्त्वों का प्रयोग कम कुशलता के साथ भी किया जा सकता
है और अधिक कुशलता के साथ भी। एक विशेष देश में किसी विशेष समय शक्ति
का एक तत्त्व अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है जबकि दूसरे समय में उसका महत्व
इतना नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, एक हथियार का शक्ति-मूल्य इस बात
पर निर्भर करता है कि वह रणनीति में किस स्थान पर कार्य कर रहा है। मई, 1940
में जब फ्रांस पर हिटलर का आक्रमण हुआ तो उस समय फ्रांस की अपेक्षा जर्मनी
के हाथों में एक टैंक का मूल्य अधिक था।

पाँचवें, वर्तमान युग तकनीकी विकास का युग है। इस काल में परिवर्तन
बड़ी तीव्र गति से हो रहे हैं। शक्ति के विभिन्न तत्त्व जो कभी पर्याप्त महत्वपूर्ण थे
आज उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं तथा अन्य नए महत्वपूर्ण तत्त्वों का विकास होता
जा रहा है। पहले कोयले की ईंधन का मुख्य स्रोत माना गया था, किन्तु बाद में
इसका स्थान तेल ने ले लिया। तेल का स्थान यूरेनियम लेता जा रहा है। यह भी
सम्भव है कि विज्ञान का विकास यूरेनियम को भी महत्वहीन बना दे। ठीक इसी
प्रकार हथियार भी असामयिक बन जाते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के
साथ-साथ शक्ति के कम दृश्य तत्त्वों में भी परिवर्तन होता रहता है। जब कभी
सरकार की कुशलता एवं जनता के मनोबल में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं तो इसके
कारणवश शक्ति-सम्बन्धों में भी गम्भीर परिवर्तन आ जाते हैं।

छठे, तैयारी के पहलू को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। अतीत काल में भी
रणनीतियाँ तय करते समय सिपाहियों के बीच इस आधार पर भेद किया जाता था
कि वे हथियारों से लेंस तथा युद्ध के लिए तैयार हैं अथवा नहीं। जो सैनिक सशस्त्र
खड़े हैं वे उनसे अधिक मूल्यवान हैं जिनको कि तैयार होने में समय लगेगा। आज
का जमाना बटन को दबा कर युद्ध करने का जमाना है। ऐसी स्थिति में दमबारी
करने वाला वह जहाज जिसे उड़ने के लिए कुछ घण्टे चाहिए, उस जहाज से भिन्न
है जो दमबारी के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि अचानक ही आक्रमण कर दिया
जाए तो वह दम-वर्षक जहाज निरर्थक रहेगा जिसे तैयार होने के लिए कुछ समय
की जरूरत है। यही बात शक्ति के अन्य तत्त्वों पर भी इसी प्रकार लागू होती है।
यदि वे क्रियान्वित होने के लिए तैयार हैं तब तो ठीक है, वरना उनका महत्व एवं
प्रभाव उतना नहीं रहेगा।

इस प्रकार जब भी किसी राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन किया जाए तो उसके
विश्लेषण को केवल प्राप्त आँकड़ों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए वरन् उनको

भावी प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में देखना चाहिए। यहाँ एक समस्या यह उठ खड़ी होती है कि विश्वसनीय सांख्यिकीय एवं अनुमानों तथा उनके समय के बीच किस प्रकार सम्बन्ध स्थापित किया जाए। राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति सापेक्ष होने के कारण एक अन्य समस्या यह उठती है कि दूसरे देश की शक्ति को किस प्रकार जाना जाए। केवल अनुमानों एवं सम्भावनाओं के आधार पर किया गया मूल्यांकन कई बार गलत साबित होता है।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या

(Elements of National Power Briefly Explained)

राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न आधारभूत तत्वों का विस्तार से विवेचन अगले अध्याय में किया गया है, तथापि पृष्ठभूमि के रूप में उनका संक्षिप्त विवेचन अपेक्षित है—

भूगोल (Geography)

यह राष्ट्रीय शक्ति का सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। अतीत का इतिहास साक्षी है कि राष्ट्र की शक्ति, सम्यता और विकास पर उस देश की भौगोलिक स्थिति का अनेक अवसरों पर निर्णायक प्रभाव पड़ा है। आज यातायात तथा सैनिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक और दुर्गामी आविष्कारों के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है तथा कोई भी देश या स्थान अनुलब्धीय नहीं है, तथापि भूगोल या भौगोलिक स्थिति के महत्त्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वियतनाम की भौगोलिक स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण ही अमेरिका विपुल सैन्यबल के प्रयोग के बावजूद विजयी नहीं हो सका। रूस के सुविस्तृत भू-क्षेत्र कड़कड़ाती सर्दियों आदि ने नाज़ी जर्मनी के भयानक और विद्युत आक्रमण से न केवल उसकी रक्षा की बल्कि नाज़ी सेनाओं का इतना विनाश किया कि महायुद्ध का पासा ही जर्मनी के विरुद्ध पलट गया। भारत के उत्तर में गगनचुम्बी हिमालय पर्वतशृंखला यद्यपि आज अभेद्य नहीं रही है, तथापि देश की रक्षा के लिए उसका सैनिक महत्त्व चिरपरिचित है।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल का अध्ययन करते समय यह आवश्यक है कि हम इसके चार मुख्य भागों पर ध्यान दें—आकार (Size), जलवायु (Climate), भूकृति (Topography) एवं स्थिति (Location)। ये विभिन्न बातें देश-विदेश के भौगोलिक तत्वों को महत्त्व प्रदान करती हैं। उदाहरणार्थ, बड़े आकार वाले राष्ट्र में बड़ी जनसंख्या रह सकती है, विभिन्न खनिज-पदार्थों की सम्भावना हो सकती है, आक्रमणकारी सेनाओं को दूर तक पीछे हटते हुए धकाया और फेंकाया जा सकता है, आदि। जलवायु की दृष्टि से ठण्डे देशों के लोग प्रायः गरम देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक उद्यमी होते हैं, अतएव अधिक ठण्डे और बर्फीले भू-भाग वाले देश को जीतना मुश्किल नहीं होता, अतिशय गर्म देश को खाद्य-स्थिति को चिन्ताजनक बनाए रखती है, आदि। भूकृति की दृष्टि में जिन राष्ट्रों की सीमा प्रकृति द्वारा निर्धारित हो वहाँ प्रायः सीमा-संघर्ष के प्रश्न नहीं उठते, बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए व्यूह-रचना की सुविधा होती है, आदि। स्थिति की दृष्टि में देश

की प्रत्येक-व्यवस्था और नीतियाँ प्रभावित होती हैं, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव-क्षमता कम या अधिक होती है, आदि । समुद्रों से घिरे होने के कारण ही जापान और इंग्लैण्ड सामुद्रिक शक्ति बन सके हैं, राष्ट्रों से घिरा होने के कारण बेल्जियम अपनी सुरक्षा के लिए फ्रॉम तथा इंग्लैण्ड का समर्थक रहा है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही भारत बहुत कुछ तटस्थता की नीति पर चलने को प्रेरित हुआ है ।

अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण और निर्धारण में भौगोलिक तत्त्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके प्रभाव को बहुत बढ़ा-बढ़ा कर मानना भी समुचित नहीं है । आज की अरिबन्धित परिस्थितियों में भूगोल राष्ट्रीय शक्ति को सीमित रूप से ही निर्धारित करता है ।

प्राकृतिक साधन (Natural Resources)

राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्त्वों में प्राकृतिक साधन का विशेष महत्त्व है । प्राकृतिक साधन राष्ट्र की पूँजी होते हैं, लेकिन तभी जबकि राष्ट्र उनका समुचित विदोहन और उपयोग कर सके । प्राकृतिक साधनों में खाद्यान्न और कच्चा माल दोनों गिने जाते हैं । कच्चे माल में खनिज पदार्थ, वातस्पतिक उत्पादन तथा पशुओं द्वारा उत्पादित माल शामिल किए जाते हैं । खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म-निर्भर राष्ट्र निश्चित रूप से उस देश की अपेक्षा लाभ की स्थिति में होता है जो समुचित मात्रा में खाद्यान्न पैदा न कर सकने के कारण हमेशा दूसरे देशों से उनका आयात करता है । कच्चे माल के बिना देश का औद्योगिकरण असम्भव है । कच्चे माल में भी कोयला, लोहा और पेट्रोल मुख्य हैं क्योंकि ये तीनों ही वस्तुएँ आधुनिक उद्योग-व्यवस्था तथा व्यवसाय के आधार हैं । कोई भी राष्ट्र आर्थिक और सैनिक दृष्टि से तब तक सबल नहीं हो सकता जब तक कि ये तीनों वस्तुएँ उसे सुलभ न हों ।

जनसंख्या (Population)

मानव-शक्ति किसी भी राष्ट्र की निर्बलता और सबलता का कारण हो सकती है । यदि जनसंख्या विचाल है पर कार्यक्रम नहीं है अथवा उसके समुचित पालन-पोषण के लिए प्राकृतिक साधनों का अभाव है, तो वह जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में सहायक न होकर बाधक सिद्ध होगी । दूसरे ओर, प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न देश की कार्यशील और क्षमतावान जनसंख्या उस देश के लिए अथवा राष्ट्रीय शक्ति के द्वार खोल देगी । जनसंख्या चाहे कम हो, लेकिन उसका गुणी होना, क्षमतावान होना, शिक्षित होना प्रतिआवश्यक है । छोटी-सी मानव-शक्ति का घनी राष्ट्र जापान या जर्मनी या ब्रिटेन अन्तर्राष्ट्रीय अगत् में क्या-क्या परिश्रम दिखा चुका है यह किसी से छिपा नहीं है । अभिप्राय यह है कि राष्ट्रीय शक्ति के सन्दर्भ में जनसंख्या का अध्ययन करते समय राष्ट्र के निवासियों की संख्या-मान के आधार पर परिणाम निश्चित नहीं किया जा सकता । निवासियों की संख्या के साथ-साथ हमें यह भी जानना होगा कि निवासी किस प्रकार के, कितने परिश्रमी हैं और उनमें भविष्य में क्या करने की सामर्थ्य और आकांक्षा है ।

प्राविधिक ज्ञान (Technology)

प्राविधिक ज्ञान का मूल्योत्कृष्ट राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और शक्ति के अन्य तत्वों के सन्दर्भ में किया जाता है। इसमें यान्त्रिक पद्धतियों के विकास, रणनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, संचार-साधनों की प्रगति आदि वे विभिन्न बातें सम्मिलित हैं जो राष्ट्रीय शक्ति के विकास में सहायक होती हैं। प्राविधिक ज्ञान में सैनिक और औद्योगिक दोनों ही तकनीकी विकास शामिल किए जाते हैं। सैनिक तकनीक पर राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक तकनीक पर राष्ट्रीय आय एवं देश की औद्योगिक संरचना निर्भर करती है। प्राविधिक ज्ञान राष्ट्रीय शक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे—यह राष्ट्र के स्वरूप को बदल देता है, राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक संरचना को गतिशील बना कर, देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता को अर्थपूर्ण बनाता है, आदि। अपने महान् सैनिक और औद्योगिक तकनीकी विकास के बल पर सोवियत रूस, अमेरिका, जर्मनी और जापान विश्व के अग्रणी राष्ट्र बने हुए हैं। वैज्ञानिक संचार-साधनों की प्रगति के अनुपात में ही राजनीतिक समुदाय का आकार विकसित होता है। बिना सुविकसित प्राविधिक ज्ञान के संचार-साधनों की प्रगति नहीं हो सकती। प्राविधिक ज्ञान के विकास ने वास्तव में आज विश्व को दोराहे पर ला खड़ा किया है। एक ओर तो राष्ट्र अपनी युद्ध-तकनीक का विस्तार करके विश्व को विनाश की ओर धकेल रहे हैं और दूसरी ओर रचनात्मक साधनों के अधिकाधिक निर्माण द्वारा मानवता को दुःख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं। प्राविधिक ज्ञान ने विश्व को इतना छोटा बना दिया है कि या तो सम्पूर्ण दुनिया के लोग मिल कर सहयोग के साथ चलें अथवा अपने आप को समाप्त कर देने का रास्ता पकड़ लें।

विचारधारा (Ideology)

पेडलफोर्ड तथा लिंकन के अनुसार विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का निकाय है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। विचारधारा व्यक्तियों और समूहों को एक ऐसे समाज में बाँध देती है जो सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समान तरीकों में विश्वास करते हैं। अग्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव राष्ट्रीय शक्ति के विकास पर पड़ता है। जिस विचारधारा को एक देश मानता है उस विचारधारा को मानने वाले अन्य देशों की सद्भावना और मंत्री उसके प्रति रहना स्वाभाविक है। सैद्धान्तिक विचारधाराएँ आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रीय शक्ति के प्रभाव-विस्तार में कितना योग दे रही हैं और क्या करतब दिखा रही हैं, यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रत्येक माधारण छात्र जानता है। साम्यवाद की सैद्धान्तिक शक्ति को इतिहास के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के आधार पर बढ़ाया जाता है और पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद पर श्रमिक वर्ग की विजय का दावा किया जाता है। नैकतान्त्रिक विचारधारा साम्यवाद के प्रसार पर अडगुन रखने के नाम पर अपने राष्ट्रों के माध्यम में साम्यवादी विश्व को घेरने और सीमित रखने को प्रयत्नशील

है। फासिस्ट और नाजी विचारधाराओं ने इटली और जर्मनी की विस्तारवादी आकांक्षाओं को किस कदर बढ़ाया था, यह सभी जानते हैं। विचारधाराएँ वास्तव में ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रों की विदेश-नीतियों को प्रवर्धित रूप में प्रभावित करती हैं और अप्रत्यक्ष रूप में शक्ति-संघर्ष का माध्यम बनती हैं। विचारधाराएँ राष्ट्रीय मनोबल को उठा कर राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करती हैं।

मनोबल (Morale)

यह राष्ट्रीय शक्ति का कोई स्थायी तत्त्व नहीं है, तथापि एक ऐसा तत्त्व है जो संकटकाल में सम्पूर्ण राष्ट्र को प्रेरणा देता है, उसकी वास्तविक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। माॅर्गेन्यो के अनुसार, "राष्ट्रीय मनोबल एक ऐसा निश्चय है जिसके द्वारा जनता युद्ध अथवा शांति में राष्ट्र की विदेश-नीति का समर्थन करती है। यह एक ऐसा तत्त्व है जो लोकमत का निर्माण करता है तथा जिसके समर्थन में कोई भी सरकार चाहे वह लोकतन्त्रीय हो या अधिनायकवादी, अपनी नीतियों को मनवा सकती है।" मनोबल कभी-कभी युद्ध के प्रतिरोध के रूप में भी काम करता है अर्थात् जिस देश के लोगों में एकता होनी है और जिस प्रकार की नीतियों के पीछे सारी जनता का बल होना है, उस देश पर सहसा ही कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। राष्ट्रीय चरित्र, संस्कृति, नेतृत्व, अच्छी सरकार, देश की परिस्थितियाँ आदि विभिन्न तत्त्व मनोबल का निर्माण करते हैं। लोकतान्त्रिक राज्यों में लोकमत के रूप में मनोबल देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को जिसका प्रभावित करता है उतना अधिनायकवादी राज्यों में नहीं लेकिन अपवाद भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, हिटलर की विदेश-नीति को लगभग 90 प्रतिशत से भी अधिक जर्मन जनता का समर्थन प्राप्त था। अपने अपार मनोबल के कारण ही धकेला जर्मनी अनेक सुविशाल और शक्तिशाली राष्ट्रों को छोटी का दूध पिला सका। यदि सेना का मनोबल गिर जाए, राष्ट्र का मनोबल टूट जाए, तो राष्ट्रीय शक्ति के अन्य प्रभावशाली तत्त्व भी विपरीत रूप में प्रभावित होकर अपनी क्षमता खो बैठते हैं।

नेतृत्व (Leadership)

राष्ट्रीय शक्ति का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्त्व है। प्रायः नेतृत्व की महानता और निपुणता पर ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत में किसी देश का सम्मान और प्रभाव निर्भर करता है। योग्य नेतृत्व के अभाव में शक्तिशाली राष्ट्र भी शीघ्र ही निबल हो जाएगा। यदि योग्य सेनापति न हो तो एक विशाल और सुसज्जित सेना भी अपेक्षाकृत छोटी सेना से, जिसका संचालन कुशल सेनापतियों के हाथ में है, हार जाएगी। नेतृत्व मुख्य रूप से दो रूपों में राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है—प्रथम, यह राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करता है एवं दूसरे, राष्ट्रीय शक्ति को गति और विकास देता है। भारत की सौभाग्यवश सदैव ही सुयोग्य और कुशल नेतृत्व मिला जबकि पाकिस्तान को नहीं और इसके परिणाम स्पष्ट हैं। बंगलादेश की गेल मुजीब का कुशल नेतृत्व मिला जिससे एक गुलाम जनता सम्प्रभु जनता के रूप में परिवर्तित हो गई।

उपर्युक्त सभी तत्त्व मिलकर राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करते हैं। सभी तत्त्व सम्बद्ध होते हैं, एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और समुक्त रूप से राष्ट्र को शक्ति प्रदान करते हैं। अतः किसी एक तत्त्व के आधार पर राष्ट्रीय शक्ति के मूल्यांकन के प्रलोभन से हमें बचना चाहिए। जो तत्त्व गतिशील और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं उन्हें अधिनाधिक सशक्त और उपयोगी बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयास होना चाहिए। उदाहरणार्थ, राष्ट्र की जनसंख्या के गुण और कार्य-क्षमता का निरन्तर विकास किया जाना चाहिए। यह तथ्य कभी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि केवल विभिन्न तत्त्वों की उपस्थिति से ही राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण अथवा विस्तार हो जाएगा। मूल आवश्यकता इस बात की है कि उपलब्ध तत्त्वों का प्रभावशाली रूप में समुचित उपयोग किया जाए और यदि कोई तत्त्व निर्वल या पिछड़ा हुआ है तो इस कमी को यथासाध्य दूर किया जाए। एशिया और अफ्रीका के बहुत से राष्ट्र प्राविधिक ज्ञान की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, अतः अपेक्षित है कि वे उन्नत देशों से उसका आयात करें, अपने देश में इसकी सुदृढ़ नींव डालें और स्वयं को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयत्न करें। विभिन्न तत्वों की प्रचुरता और सम्पन्नता के आधार पर तथा उनके समुचित उपयोग से एक प्रचण्ड राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण सम्भव है, लेकिन हम किसी राष्ट्र के उत्थान या पतन के कारणों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं कर सकते। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के भँवर में फँस कर अथवा युद्ध की चपेट में आकर सर्वसाधनसम्पन्न राज्यों का भी पतन होते देखा गया है।

राष्ट्रीय शक्ति का उत्थान और पतन

राष्ट्रीय शक्ति के सार और तत्त्व के प्रसंग में हमें राष्ट्रीय शक्ति के उत्थान और पतन पर भी सक्षेप में विचार कर लेना चाहिए। चूँकि शक्ति की प्राप्ति और रक्षा मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि सम्बन्धित राष्ट्र शक्ति के अवयवों अथवा तत्वों का उपयोग उचित रीति से कहाँ तक कर पाते हैं, और शक्ति-तत्वों के उचित उपयोग का प्रश्न स्वयं अनिश्चित प्रकार का है, अतः स्वाभाविक है कि ऐसा कोई सुनिश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता जिसके अनुसार राष्ट्र शक्ति पाते अथवा खोते हों। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में अभी तक ऐसे किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन नहीं हो पाया है और न ही व्यवहार में किसी राष्ट्र ने ऐसा कोई पक्का नियम कार्यान्वित किया है कि हम इस प्रकार का निर्णय कर सकें कि कोई राष्ट्र नव शक्ति प्राप्त करता है और नव उसे खो बैठता है अथवा कुछ समय के उत्कर्ष के बाद राष्ट्रीय शक्ति का पतन कब हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि अनेक राष्ट्र शक्ति पाकर ऊँचे उठे, विश्व में उन्होंने अपना शक्ति-ध्वज फहराया, अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया, फिर वे पतन की ओर उन्मुख हुए और लुप्त भी हो गये। इन राष्ट्रों के इतिहास से हमें यह अनुमान तो होता है कि विभिन्न तत्वों के सहयोग से कोई राष्ट्र शक्ति ग्रहण करता है और विभिन्न तत्वों अथवा किसी तत्व विशेष के ह्रास से वह राष्ट्र अपनी शक्ति खोने लगता है तथा पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। किन्तु किसी तत्व विशेष को ही सुनिश्चित नहीं किया

जा सकता अथवा राष्ट्रीय शक्ति के उत्थान और पतन का कोई पक्का नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः राष्ट्रीय शक्ति के उदय, उत्कर्ष और पतन के पीछे कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे ठीक से समझ पाना मुश्किल है। हैन मॉर्गेंथो के विवरणानुसार राष्ट्रों का उत्थान और पतन ऐसी विविध और बहुरूपी परिस्थितियों का परिणाम होता है जिन पर व्यक्ति तथा राष्ट्र का साधारणतया कोई बश नहीं होता। इतिहास बनाना है कि कभी किसी राष्ट्र का अथवा राष्ट्रीय शक्ति का उदय उस राष्ट्र के किसी महापुरुष के कारण हुआ तो कभी संनिक तत्त्व ने राष्ट्रीय शक्ति के उदय और उत्कर्ष में सर्वोपरि भूमिका निभाई तो कभी आर्थिक तत्त्व ने किसी राष्ट्र को प्रभुता प्रदान की। नैपोलियन फ्रांस के उत्थान के लिए, लेनिन बोल्शेविज्म के उत्कर्ष के लिए, मुसोलिनी इटली में फासीवाद के उदय और उत्कर्ष के लिए तो हिटलर नازیवाद के प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी रहे हैं। व्यक्तियों की महानता के कारण राष्ट्रीय शक्ति के उदय और उत्थान के ये उदाहरण हैं। वर्तमान में कतिपय अरब राष्ट्रों का 'तेल' उनकी राष्ट्रीय शक्ति का मुख्य आधार बना हुआ है—यहाँ तक कि एक अरब देश की 'तेल-नीति' समस्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के घटनाचक्र को नया मोड़ देने की शक्ति रखती है। वस्तुनिष्ठ कारणों का राष्ट्रों के उत्थान और पतन में भारी महत्त्व होता है और इन पर राष्ट्रों का कोई बश नहीं होता। इसके दो सशक्त उदाहरण हैं—एक तो दोनों महायुद्धों के बीच के काल में और दूसरा महायुद्धों के बाद में ब्रिटेन का पतन तथा अमेरिका का दीर्घकालीन एकान्तवासी के बाद अभ्युदय।

राष्ट्रीय शक्ति के उदय और उत्कर्ष की दृष्टि से घरेलू अथवा स्वराष्ट्रीय शासन का क्षेत्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति और महानता बनाए रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसमें अपनी संस्थाओं को जीवित करने, पुनः समायोजन करने, अपनी नीति में समायोजन-परिवर्तन करने, नवीन कार्यों में प्रवेश करने, नवीन चुनौतियों का सामना करने, अपने विचारों का नए सिरे से मूल्यांकन करने आदि की सामर्थ्य हो। इसके अतिरिक्त, जैसा कि डॉ. महेन्द्रकुमार ने लिखा है : “शक्ति चूंकि अन्य राज्यों के व्यवहार पर प्रवर्तक या निवर्तक शक्ति से प्रभाव डालने की सामर्थ्य का नाम है, इसलिए इस शक्ति की प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि सभी की जा सकती है जब इसके सब घटक अवयवों का चतुराई और सूक्ष्मता से उपयोग किया जाए, क्योंकि साधनों या शक्ति के अवयवों के उपयोग में अक्षिप्त पंखा होती है और उसी से राष्ट्र शक्तिशाली बनता है।”

राष्ट्रीय शक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में

शक्ति-स्तर का वर्गीकरण

राष्ट्रीय शक्ति के उत्कर्ष के अनुरूप विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति का स्तर अलग-अलग होता है। इसीलिए कुछ राष्ट्र ‘बड़े राष्ट्र’ तो कुछ ‘छोटे राष्ट्र’ कहलाते हैं। बड़े राष्ट्रों को ‘महाशक्ति’ (Great Power) की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। किन्तु परमाणु शक्ति के प्रसार और स्वामित्व के साथ-साथ ‘महानतम शक्तियों’ (Super Powers) का भी उदय हुआ है। हमें देखना चाहिए कि

राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न स्वामियों में यह शक्ति-स्तरीय भिन्नता किस रूप में है। जो राष्ट्र विशाल भूक्षेत्र और विशाल जनसंख्या वाले होते हैं उनको भी प्रायः 'बड़ा देश' की संज्ञा दी जाती है—जैसे कि भारत और चीन। ये दोनों राष्ट्र राष्ट्रीय शक्ति के दो मुख्य तत्वों—भूभाग और जनसंख्या—की दृष्टि से धनी हैं पर साथ ही आर्थिक और सैनिक तत्व की दृष्टि से भी प्रबल होते जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ये दोनों ही राष्ट्र 'राष्ट्रीय शक्ति' की दृष्टि से बहुत ही अग्रणी राष्ट्र बन जायेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। फिर भी इन्हें रूस और अमेरिका के समकक्ष नहीं माना जा सकता क्योंकि रूस और अमेरिका राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों की दृष्टि से जितने अधिक धनी हैं उतने अधिक धनी भारत या चीन नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारकों ने कुछ अरसे पूर्व तक पाँच महाशक्तियाँ गिनाई थी—ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। यह वर्गीकरण अब कुछ अर्थार्थ या लगता है क्योंकि ब्रिटेन अपना पुरातन वैभव और प्रभाव खो चुका है जबकि भारत यथार्थ में एक महाशक्ति के रूप में तेजी से उभर आया है और उसे चीन की तुलना में कम करके नहीं आका जा सकता। दूसरी और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अणुशक्ति, सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के बल पर 'महानतम शक्ति' (Super Power) बन गये हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, भारत या चीन अथवा कोई भी अन्य देश रूस अथवा अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, ये दोनों राष्ट्र शक्ति और प्रभाव की दृष्टि से अन्य सभी राष्ट्रों की तुलना में बहुत-बहुत आगे हैं। हमें, अधिक स्पष्टता के लिए, महाशक्ति और महानतम शक्ति के अन्तर को समझ लेना चाहिए।

वास्तव में 'महाशक्तियों' (Great Powers) के संप्रत्यय का जन्म 1815 के वियना सम्मेलन में हुआ और इसलिए इसे 19वीं सदी का संप्रत्यय माना जाता है। दीर्घकाल तक रूस और अमेरिका दोनों ही की गणना विश्व की महाशक्तियों की जाती रही क्योंकि इन दोनों ही की शक्ति का स्तर लगभग बँसा ही रहा जैसा पहले ब्रिटेन और फ्रांस जैसी महाशक्तियों का रहा था। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त ब्रिटेन और फ्रांस की शक्ति का पराभव खोता चला गया जबकि सोवियत संघ और अमेरिका ने न केवल अपने महाशक्ति के स्तर को बनाये रखा बल्कि अन्य सभी देशों की तुलना में सैनिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक दृष्टि से अत्यधिक श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। आज रूस और अमेरिका ऐसी जबरदस्त शक्तियाँ बन चुकी हैं कि विश्व को मोटे तौर पर दो खेमों में विभाजित करके देखा जाता है—रूसी खेमा और अमेरिकी खेमा।

महाशक्ति और महानतम शक्ति के संप्रत्ययों का एक अच्छा विश्लेषण डॉ. महेन्द्रकुमार ने किया है जो उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है—

महाशक्ति और महानतम शक्ति का भेद समझने के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि किसी महाशक्ति से हमारा अभिप्राय किसी ऐसे राष्ट्र से होता है जो किसी दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों पर अपनी इच्छा तो थोप सके परन्तु उन दूसरे राष्ट्रों का उस पर कोई प्रभाव न हो। इस प्रकार अपनी इच्छा दूसरे राष्ट्र पर

घोष सकने वाला राष्ट्र महाशक्ति कहलाता है और जिस राष्ट्र पर इच्छा घोषी जाती है वह छोटा राष्ट्र कहलाता है। महानतम् शक्तियों का प्रादुर्भाव होने के पहले स्थिति यह थी कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी अनेक महाशक्तियाँ थी जो छोटे राष्ट्रों पर अपनी इच्छा लाद सकती थी। ये महाशक्तियाँ अपने-अपने अलग-अलग ढंग से छोटे राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयत्न करती थीं परन्तु ऐसा करते समय प्रत्येक महाशक्ति इस बात के लिए भी प्रयत्नशील रहती थी कि किसी दूसरी महाशक्ति का छोटे राष्ट्रों पर प्रभाव इतना न बढ़ जाय कि स्वयं उसके अपने महाशक्ति के दर्जे को खतरा पैदा होने लगे। इसलिए प्रत्येक महाशक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह अन्य महाशक्तियों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए निरन्तर प्रयास करती रहे। यह प्रयास अक्सर शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त के द्वारा किया जाता था परन्तु प्रत्येक महाशक्ति के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह अपना महाशक्ति का स्तर सदैव बनाये रखे। बहुधा यह देखने में आता था कि यदि कोई राष्ट्र कुछ समय के लिये महाशक्ति बन जाता था तो बाद में वह कभी-कभी द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र की स्थिति में पहुँच जाता था। इसी प्रकार कभी-कभी कोई छोटा राष्ट्र भी महाशक्ति बन जाता था। इस प्रकार महाशक्ति और छोटे राष्ट्र का भेद अस्थायी ही होता था और इस भेद की सार्यकता केवल उस समय तक ही रहती थी जब तक कि किसी महाशक्ति को किसी युद्ध में भाग न लेना पड़े। परन्तु जब-जब युद्ध होता था तब-तब महाशक्ति के स्तर को खतरा उत्पन्न हो जाता था। इतना ही नहीं, समय-समय पर होने वाले युद्ध के परिणाम भी स्थायी नहीं होते थे। अर्थात् यह आवश्यक नहीं था कि यदि कोई देश एक बार किसी युद्ध में विजयी होकर महाशक्ति का दर्जा प्राप्त कर ले तो उसका यह दर्जा हमेशा बना रहे। महाशक्ति का दर्जा हमेशा बनाये रखने के लिए यह आवश्यक था कि वह देश बार-बार युद्ध में विजयी होकर अपनी सैनिक श्रेष्ठता स्थापित करता रहे परन्तु ऐसा अक्सर असम्भव होता था। इसलिए जब कोई राष्ट्र युद्ध में विजयी हो जाता था तो वह महाशक्ति बन जाता था और उसका यह स्तर उस समय तक कायम रहना था जब तक कि उसे अगले युद्ध में भाग न लेना पड़े। इस प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त करने पर महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होता था और युद्ध में पराजित होने पर वही देश द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र बन जाता था।

उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक महाशक्ति की एक मुख्य विशेषता यह रही कि किसी भी क्लासिकी महाशक्ति का दर्जा स्थायी नहीं होता था, क्योंकि उस समय कई राष्ट्र एक साथ छोटे राष्ट्रों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते थे। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र के क्रियाकलापों पर अन्य बड़े राष्ट्रों की होड़ के कारण कुछ प्रतिबन्ध लग जाते थे।

महानतम् शक्ति की मुख्य विशेषता यह है कि उसके क्रियाकलापों पर इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। आज की महानतम् शक्ति अर्थात् सुपर पावर उन्नीसवीं शताब्दी की महाशक्ति अर्थात् ग्रेट पावर से इस अर्थ में भिन्न है कि महानतम् शक्ति के सामने ऐसे अन्य बड़े प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र नहीं हैं जिनके पास उतनी

ही सैन्य शक्ति हो जितनी कि महाशक्ति के पास, या जो छोटे राष्ट्रों पर उतना ही प्रभाव डाल सकते हों जितना कि एक महानतम् शक्ति डाल सकती है। न ही दूसरे राष्ट्र किसी महानतम् शक्ति को अपना प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पर डालने से रोक सकते हैं। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और आस्ट्रिया जैसे देश इसलिए महाशक्ति कहलाते थे कि वे सभी अपने-अपने ढंग से दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते थे, क्योंकि इन सभी बड़े राष्ट्रों की शक्ति लगभग बराबर होनी थी इसलिए उनमें से प्रत्येक राष्ट्र की महाशक्ति का स्तर अन्य शक्तियों के कारण सीमित हो जाता था परन्तु आज स्थिति बदल गई है। कारण यह है कि अमेरिका और सोवियत संघ अब केवल प्राचीन अर्थ में महान शक्तियाँ नहीं हैं बल्कि उनकी शक्ति का स्तर अब अत्यधिक बढ़ गया है। वैसे तो साधारण अर्थ में ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन सभी महाशक्तियाँ कहलाते हैं। परन्तु सोवियत संघ और अमेरिका की सैन्य शक्ति अन्य तीनों महान शक्तियों की अपेक्षा इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब उनको महान शक्तियों की एक विशिष्ट श्रेणी में रखना आवश्यक हो गया है। यह विशिष्ट श्रेणी ही महानतम शक्ति अर्थात् सुपर पावर की श्रेणी है। इस प्रकार सोवियत संघ और अमेरिका महानतम् शक्तियों की श्रेणी में आते हैं और फ्रांस, ब्रिटेन और चीन महाशक्तियों की श्रेणी में आते हैं।

आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही अपनी-अपनी इच्छा छोटे राष्ट्रों पर निर्द्वन्द्व होकर लाद सकते हैं क्योंकि उनके जियाकलापो पर फ्रांस, ब्रिटेन और चीन कोई भी बन्धन नहीं लगा सकता। परन्तु यदि फ्रांस, ब्रिटेन, या चीन में से कोई भी महाशक्ति छोटे राष्ट्रों पर नियन्त्रण करना चाहे तो वह ऐसा केवल उभी सीमा तक कर सकता है जहाँ तक सोवियत संघ और अमेरिका उसे करने दें। इस प्रकार क्लासिकी महाशक्ति और आधुनिक महानतम् शक्ति के भेद का मुख्य आधार यह है कि विभिन्न महाशक्तियों के निर्द्वन्द्व व्यवहार पर प्रकुश लगाने की जो पारस्परिक क्षमता पहले पाई जाती थी वह अब समाप्त हो गई है।

यहाँ तक बतला देना आवश्यक है कि इस प्रकार की पारस्परिक क्षमता केवल आंशिक रूप में ही समाप्त हुई है, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच यह पारस्परिक क्षमता अब भी पाई जाती है। कहने का आशय यह है कि सोवियत संघ और अमेरिका एक-दूसरे को अब भी अपनी इच्छा दूसरे देशों पर थोपने से उभी प्रकार रोक सकते हैं जिस प्रकार दूसरे महायुद्ध के पहले पाँच बड़े राष्ट्र आपस में एक-दूसरे को समझौता करते से रोक सकते थे। इस प्रकार महाशक्ति का दुरस्त सम्वन्ध अब केवल सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में ही लागू होना है। इसका कारण यह है कि उपग्रहीय शक्तियों के बहुध्रुवीय निकाय का स्थान अब द्विध्रुवीय निकाय में ले लिया है। द्विध्रुवीय निकाय के प्रादुर्भाव के कारण महाशक्ति और महानतम् शक्ति में भेद करना अब आवश्यक हो गया है। दूसरे महायुद्ध के बाद

यदि द्विध्रुवीयता का जन्म न होता तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वही सिलसिला चलता रहता जिसमें बराबर की शक्ति वाले कुछ महान् राष्ट्र अपनी मनमानी करते थे। वास्तविकता यह है कि वर्तमान काल में केवल सोवियत संघ और अमरीका ही दो ऐसे देश हैं जिनकी सैन्यशक्ति एक-दूसरे के लगभग बराबर है। इसलिए महानतम शक्ति का संप्रत्यय केवल सोवियत संघ और अमरीका के सन्दर्भ में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि इन दो राष्ट्रों की सैन्यशक्ति उन समस्त अन्य देशों की शक्ति से बहुत अधिक है जिन्हें परम्परागत रूप से महाशक्तियाँ माना जाता था।

राष्ट्रीय शक्ति-स्तर में उनाट-चढ़ाव के साथ अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रों के विकास और ह्रास की प्रक्रिया चलती रहना स्वाभाविक है। जो आज छोटा राष्ट्र है, वह राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों के विकास के बल पर कल बड़ा राष्ट्र या महाशक्ति या महानतम शक्ति बन सकता है। आज का युग परमाणु शक्ति का युग है और महाशक्ति तथा महानतम शक्ति का ध्येय मुख्यतः इसी बात पर निर्भर है कि कौन देश कितनी विशाल और सक्षम परमाणु शक्ति का स्वामी है। यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी देश का महानतम शक्ति का दर्जा किन्हीं अन्य महाशक्तियों के सन्दर्भ में ही माँका जा सकता है। डॉ. महेन्द्र कुमार ही के शब्दों में महाशक्ति और महानतम शक्ति के बीच भेद करते समय हमें पहले उन सभी राष्ट्रों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए जो दूसरे महायुद्ध तक महाशक्तियाँ कहलाते थे और फिर उनको महाशक्तियों एवं महानतम शक्तियों की दो श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए। सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन सभी देश दूसरे महायुद्ध तक बराबर की हैसियत की महाशक्तियाँ कहलाते थे परन्तु दूसरे महायुद्ध के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और चीन की महाशक्ति का दर्जा वह नहीं रहा जो कि अब सोवियत संघ और अमरीका का हो गया है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि एक ओर फ्रांस ब्रिटेन और चीन और दूसरी ओर सोवियत संघ और अमरीका ने सर्वविनाशकारी हथियार जमा कर लिए हैं वल्कि इसलिए भी कि अन्तर-राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति की भूमिका निभाने में फ्रांस, ब्रिटेन और चीन की सामर्थ्य अब बहुत कम हो गई है। फ्रांस, ब्रिटेन और चीन कुछ तो इसलिए महाशक्तियाँ कहलाते हैं कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐतिहासिक भूमिका निभायी और कुछ इसलिए कि ये तीनों देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। परन्तु यदि महाशक्ति के संप्रत्यय को उसके पुराने रूप में आज लागू किया जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस या चीन किसी को भी महाशक्ति नहीं कहा जा सकता कारण यह है कि केवल वही राष्ट्र महाशक्ति कहा जा सकता था जिसके पास किन्हीं अन्य राष्ट्रों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा दूसरे राष्ट्रों पर लादने की क्षमता हो। यह क्षमता अब केवल सोवियत संघ और अमरीका के पास ही है। फ्रांस और ब्रिटेन तथा चीन अपनी यह क्षमता खो चुके हैं।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व : भूगोल, प्राकृतिक साधन, जनसंख्या एवं प्राविधिक ज्ञान

(Elements of National Power : Geography, Natural Resources, Population and Technology)

“ 'राष्ट्रीय शक्ति' शब्द राष्ट्र की भौतिक और सैनिक-शक्ति तथा सामर्थ्य की सूचक है; किन्तु जिस व्यापक अर्थ में यह शब्द अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों में शक्ति-संघर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह इनसे भी अधिक व्यापक है। राष्ट्रीय शक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का वह योग है जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय सद्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है।” —पेंडलफोर्ड एवं लिफन

राष्ट्रीय शक्ति के आधारभूत तत्वों का प्रारम्भिक परिचय पिछले अध्याय में दिया जा चुका है पर इन तत्वों की प्रकृति कुछ ऐसी है कि विस्तृत विश्लेषण के बिना हम उनके समुचित स्वरूप और प्रभाव को नहीं आँक सकते। अतः विभिन्न प्रमुख तत्वों और उनके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा अपेक्षित है।

भूगोल (Geography)

राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में भूगोल सबसे अधिक स्थायी तत्व माना गया है। अनेक विचारकों ने तो इसके आधार पर ही एक देश की विदेश-नीति के स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। भौगोलिक राजनीतिज्ञों (Geo-Politicians) के अनुसार किसी देश की भौगोलिक स्थिति ही उसकी शक्ति अथवा निर्बलता का प्रधान कारण होती है। मैकडोवेल ने एक बार कहा था कि “एक देश की विदेश-नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है।” इस प्रकार के विचार यद्यपि अनिश्चितपूर्ण हैं, तथापि इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय शक्ति, सम्यता और विकास पर भूगोल का व्यापक प्रभाव पड़ता है। पेंडलफोर्ड तथा निक्सन के अनुसार भौतिक भूगोल अन्य तत्वों की तुलना में विश्व-राजनीति को

अधिक निरन्तर रूप से प्रभावित करने वाला तत्त्व है। यह उन प्रावश्यताओं, लक्ष्यों, नीतियों, शक्तियों आदि को प्रभावित करता है जिनको राज्य अपने हितों की दृष्टि से अपनाते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति के प्रत्येक तत्त्व का तापेक्ष महत्त्व है, अतः भूगोल के अर्थ और प्रभाव को भी अन्य तत्त्वों के सन्दर्भ में देखने पर ही हम समुचित मूल्यांकन की स्थिति में हो सकते हैं। जनसंख्या, प्राविधिक ज्ञान, नेतृत्व आदि की प्रकृति परिवर्तनशील है जिनके ससर्प से भूगोल का प्रभाव भी गत्यात्मक बन जाता है।

भूगोल-तत्त्व के अध्ययन के विभिन्न भाग

राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व के रूप में भूगोल का अध्ययन करते समय हम इसे मुख्यतः पाँच भागों में विभक्त करते हैं—मानचित्र, आकार, जलवायु, भूवृत्ति अथवा राष्ट्रीय सीमाएँ एवं स्थिति।

1 मानचित्र (Maps)—भौगोलिक तत्त्व के क्षेत्र में मानचित्रों का महत्त्व इस रूप में है कि कई बार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने के लिए मानचित्र या नक्शे का प्रयोग करता है और विश्व-जनमत को अपने पक्ष में लाने तथा उसकी सद्भावना प्राप्त करने का प्रयास करता है। भारत-चीन सीमा-सर्प के समय 'मेकमोहन रेखा' का प्रयोग और छल्लारों में प्रकाशित सीमा-मानचित्रों के सन्दर्भ में हम समझ सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नक्शों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। 13 मार्च, 1973 के दैनिक हिन्दुस्तान में समाचार था कि—“वेकिंग ने विश्व का एक नया एटलस प्रकाशित किया है जिसमें सोवियत संघ की 15 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि को चीनी क्षेत्र के रूप में दिवाया गया है। इस प्रकार चीन ने इस क्षेत्र पर दावा किया है। इससे सोवियत अधिकारी घिन्नित हो रहे हैं और उन्होंने चीन की असमान सीमा-सन्धियों के सिद्धान्त को अस्वीकृत करवाने के लिए चीन के दावे के विरुद्ध अभियान चला रखा है।”

मानचित्र को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके होते हैं—जैसे मरकेटर प्रक्षेपण विधि (Mercator Projection), समान क्षेत्रीय मानचित्र (Equal Area Maps), लम्बकोणीय प्रक्षेपण (Orthographic Projection), आदि। मानचित्र को प्रस्तुत करने का कोई भी एक तरीका पूर्ण रूप से सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता। प्रत्येक तरीके का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की दृष्टि से हम उसे सही मान सकते हैं।

2. आकार (Size)—किसी भी देश का बड़ा आकार उसके लिए जहाँ अनेक दृष्टियों से लाभकारी है, वहाँ कुछ दृष्टियों से अहितकार भी है। जैसा कि श्लोचर ने कहा है, अन्य बातों के समान होने पर एक देश जितना बड़ा होगा उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। सन् 1937 और 1945 में जापान चीन को उसके विशाल आकार के कारण ही नहीं कुचल सका। अपने बड़े आकार के कारण ही रूस ने सन् 1812 में नेपोलियन के विरुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के समय नाजी जर्मनी के विरुद्ध सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की। यदि आक्रान्त देश का आकार

सुविशाल है तो आक्रमणकारी के सामने बहुत-सी बाधाएँ प्रस्तुत हो जाती हैं, जैसे— संचार और यातायात में बड़ी कठिनाई होती है, आवश्यक वस्तुएँ समय पर और समुचित स्थान पर पहुँचने में विलम्ब होता है। यदि देश के किसी भाग पर अधिकार कर भी लिया तो वह बहुधा प्रभावकारी तथा स्थायी नहीं रह सकता।

विशाल आकार वाले देश में बड़ी जनसंख्या रह सकती है और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की प्रचुर उपलब्धि की सम्भावना रहती है। उसके महत्त्वपूर्ण औद्योगिक और सैनिक सयन्त्र सीमाओं से दूर, देश के अन्दर, सुरक्षित स्थानों पर लगाए जा सकते हैं। युद्धकाल में उस देश की सेनाएँ बहुत दूर तक पीछे हटकर शत्रु की सेना को थका सकती है और तब घेरा डालकर पराजित कर सकती हैं। द्वितीय महायुद्ध में रूसी फौजों ने यह रणनीति अपनाकर नाज़ी फौजों का सर्वनाश कर दिया था। विशालकाय देश वैज्ञानिक कृषि द्वारा आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर दूसरे देशों को अधिक अन्न का निर्यात कर सकता है और आर्थिक लाभ अर्जित कर सकता है। साथ ही इसकी आड़ में अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति भी कर सकता है। इस प्रकार आकार विभिन्न रूपों में राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि करना है।

लेकिन आकार की विशालता राष्ट्रीय शक्ति की अनिवार्य वृद्धि की गारण्टी नहीं है। देश का आकार तो सुविशाल है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य-बल नहीं है, घरती बजर है, इलाका मैदानी है और युद्ध की दृष्टि से रक्षात्मक नहीं है, जनता का मनोबल ऊँचा नहीं है, तो उस देश का आकार राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के बजाय कमजोर करेगा। जब बेकार की भूमि जनसंख्या के केंद्रों को बाँट देती है और प्रभावशाली संचार-अवस्था कायम नहीं होती, तो देश का आकार उसकी प्रगति के मार्ग में एक रोड़ा बन जाता है। दूसरी ओर छोटे आकार वाले राष्ट्र अपनी तकनीकी प्रगति, राष्ट्रीय चरित्र-बल और सुगठित औद्योगिक एवं सैनिक व्यवस्था आदि के कारण बहुत प्रगति कर लेते हैं। ब्रिटेन अथवा जापान इसके उदाहरण हैं।

यह भी स्मरणीय है कि राष्ट्र का आकार परिवर्तनशील है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र के आकार में वृद्धि और संकुचन की जितनी घटनाएँ होती हैं उतनी सम्भवतः किसी ओर तत्त्व की नहीं होती। यह आकार-परिवर्तन राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है।

3. जलवायु (Climate)—जलवायु भी एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तत्त्व है जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रायः ठण्डे देशों के लोग गर्म देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक परिश्रमी और कर्मठ होते हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति प्रभावित होती है। राष्ट्रीय शक्ति एवं उत्पादन-क्षमता पर अधिक सर्दों और अधिक गर्मों दोनों का ही अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, यदि इंग्लैंड के बन्दरगाहों पर उत्तरी यूरोपीय बन्दरगाहों की भाँति साल में 6 महीने बर्फ़ जमनी होती तो इंग्लैंड का इतिहास कुछ और ही होता। वह समुद्री शक्ति का सिरमौर बनकर अपना सुविशाल साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता था और न ही विपुल समुद्री व्यापार द्वारा अपनी आर्थिक समृद्धि की

नीव रख सकता था। भारत में वर्षा अनिश्चित न होती तो कृषि की दृष्टि से देश कभी का आत्मनिर्भर बन गया होता और उसे विदेशों की 'घन-कूटनीति' का जिकार न बनना पड़ता। अनावृष्टि या अतिवृष्टि के फलस्वरूप देश में साक्षात् की शोचनीय स्थिति ने देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा शक्ति पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डाला है, कहने की आवश्यकता नहीं। जलवायु युद्ध की दृष्टि से भी राष्ट्रीय शक्ति पर प्रभाव डालती है। खून तक को जमा देने वाली रूस की भोषणनम सर्दी ने अनेक बार आक्रमणकारी फौजों को महाविनाश के गर्त में डकेला है।

4. राष्ट्रीय सीमाएँ तथा भूकृति (National Boundaries and Topography) — जिन राष्ट्रों के मध्य पर्वत, नदी, समुद्र आदि की प्राकृतिक सीमा-रेखा होती है, उनमें सीमा-संघर्ष प्रायः नहीं उठते अथवा बहुत कम उठते हैं। इसके विपरीत जिन राष्ट्रों के बीच प्राकृतिक सीमा नहीं होती, वहाँ प्रायः सीमा-संघर्ष उठते ही रहते हैं। नदियों, पर्वतों या समुद्रों से घिरे हुए राष्ट्र उन देशों से अधिक सुरक्षित रहते हैं जिनकी सीमाएँ प्राकृतिक नहीं होती। प्राकृतिक सीमाओं से राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि होती है। ये सीमाएँ बाह्य शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करती हैं और अन्तर्देशीय व्यापार की सुविधा प्रदान करती हैं। आल्पस पर्वत-शृंखलाओं द्वारा इटली की जो रक्षा-रेखा बनी है, उसने इतिहास में कई बार इटली की विदेशी आक्रान्तों से रक्षा की है। अतीत से हिमालय भारत का उत्तरी सीमा का प्रहरी रहा है और आज भी उत्तर की ओर से आक्रमण के विरुद्ध एक रक्षात्मक ढाल के रूप में उसका महत्त्व कम नहीं है। यद्यपि वैज्ञानिक आविष्कारों के इस युग में युद्ध की दृष्टि से प्राकृतिक सीमाओं का पहले जैसा महत्त्व नहीं रहा है, तथापि इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। देश की समृद्धि आदि पर भूकृति का काफी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यूरोप की भूकृति उसके लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। अनुकूल भूकृति के कारण ही वहाँ प्राकृतिक एवं कृत्रिम बन्दरगाहों की प्रचुरता है।

प्रत्येक राज्य की सीमाएँ उन क्षेत्रों से मिली होती हैं जो अन्य सम्प्रभु राज्यों के नियन्त्रण में हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय जल को छूती हैं। प्रदेश के ऊपर का मुक्त आकाश भी राज्य की 'वायु-सीमा' में सम्मिलित होता है। ये राष्ट्रीय सीमाएँ देश की राष्ट्रीय शक्ति और स्वतन्त्रता की प्रतीक होती हैं तथा राज्य की सुरक्षा करने की योग्यता को प्रदर्शित करती हैं। राष्ट्रीय सीमा का उत्तुलघन गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न कर देता है और कभी-कभी गम्भीर युद्धों का विस्फोट कर देता है। इंग्लैंड राज्य द्वारा सीमाओं पर रक्षा-दल नियुक्त किए जाते हैं, सीमाओं की क्लिबन्दी की जाती है, सीमा पार से आने वाले लोगों की जाँच की जाती है, आदि। वर्तमान समय में ऐसीकरण की जो प्रवृत्ति बन रही है उससे यूरोप और एशिया महाद्वीपों में इन राष्ट्रीय बाधाओं का महत्त्व कम हो गया है ताकि व्यापार का संचालन और लोगों का आवागमन सुविधापूर्वक किया जा सके। रेडियो-संचार के माध्यम से भी राष्ट्रीय सीमाओं को बाँधा जा सकता है।

प्राकृतिक सीमाएँ कई बार राष्ट्र के लिए बाधक भी बन जाती हैं, उनसे

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट पड़ती है तथा राष्ट्रीय एकता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका की भूकृति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में बाधक है तो बर्मा को पर्वत-श्रृंखलाओं ने विश्व-मार्ग से पृथक् कर दिया है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच जो प्राकृतिक सीमाएँ विद्यमान थीं उनसे इस दोनो भागों की संस्कृति में अन्तर पैदा हो गया और इस स्थिति ने राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचाया है। सीमा सम्बन्धी विवाद राष्ट्रीय शक्ति को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र प्रभावित करते हैं। रूस और चीन, चीन और भारत, मिस्र और इजराइल, भारत और पाकिस्तान आदि देशों के बीच सीमा सम्बन्धी गम्भीर विवाद समय-समय पर सशस्त्र संघर्षों का रूप लेते रहे हैं। एशिया और अफ्रीका में नवीन राज्यों के निर्माण के समय उनके साथ ऐसी भूमि मिला दी गई जिस पर विश्व के दूसरे देश सहमत नहीं हैं। इन नई अपरिभाषित समस्याओं के परिणामस्वरूप काश्मीर-समस्या अरब-इजराइली संघर्ष, सोमालीलैण्ड-इथोपिया-केन्या-संघर्ष उठ खड़े हुए। राष्ट्रीय सीमाएँ प्रायः इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि सम्बन्धित राष्ट्र प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताओं का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। राष्ट्रीय सीमाओं के लिए राजनीतिक या ऐतिहासिक स्पष्टीकरण ही मान्य समझे जाते हैं। कभी-कभी सैनिक शक्ति के आधार पर भी एक देश की सीमाएँ बदली जाती हैं। जर्मनी का विभाजन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सीमाएँ इटली एवं यूगोस्लाविया की सीमाएँ इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करने में जनता के आत्म-निर्णय की मान्यता का भी पर्याप्त प्रभाव था। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का आधार मुख्य रूप से धार्मिक और साम्प्रदायिक था। वैसे जाति, धर्म, सम्प्रदाय, आदि को अधिचल रूप से राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये तत्त्व राष्ट्रीय सीमाओं को ध्यान में रखे बिना ही परस्पर विद्यमान रहे हैं।

5. स्थिति (Location)—इस भौगोलिक तत्त्व का देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राष्ट्रीय शक्ति तथा विदेश-नीति पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वि स्थिति को परिवर्तित करना देश की सामर्थ्य के बाहर है तथापि स्थिति-जन्य समस्याओं का सामना करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। स्थिति से यह बहुत कुछ स्पष्ट होता है कि देश में क्या पैदा हो सकता है, कौन-कौन से खनिज पदार्थ मिल सकेंगे, मौसम कैसा रहेगा, औद्योगिक विकास के लिए क्या परिस्थितियाँ हैं, आदि। पामर एवं पकिंस ने लिखा है कि प्रादेशिक स्थिति एक राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी सैनिक एवं आर्थिक शक्ति पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। एक देश की स्थिति वहाँ की राजनीति और युद्ध-कौशल का निर्धारण करने में भी सहयोग देती है। चारों ओर समुद्रों से घिरे होने के कारण ही जापान और इंग्लैंड वही समुद्री शक्ति बन सके हैं। राष्ट्रों से घिरा होने के कारण ही बेहजियम अपनी सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थक रहा है। अपनी विशेष केन्द्रीय स्थिति के कारण ही भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जगत् में

तटस्थता की नीति से चिपका हुआ है। अपनी स्थिति-विशेष के कारण ही बहुत से राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पाते। अमेरिका के होते हुए यह अत्यधिक कठिन है कि कनाडा, महाशक्तियों की श्रेणी में आ सके। जापान चमत्कारिक रूप से सफल और शक्तिशाली होने पर भी लाल चीन के अम्युदय के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर यह प्रभाव नहीं डाल पा रहा है जो अन्य स्थिति में होने पर वह डाल सकता था। स्थिति ही बहुत-कुछ स्पष्ट कर देती है कि कोई देश युद्ध का सखाड़ा बना रहेगा अथवा एकप्रतिरोधक राज्य (Buffer State) के रूप में काम करेगा। आशय यह है कि स्थिति का राष्ट्रीय शक्ति पर किसी न किसी रूप में अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव निश्चिन् रूप से पड़ता है।

इस विवेचन के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भूगोल राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है जिसका महत्व अन्य तत्वों की स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ बदलता रहता है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का राष्ट्रीय शक्ति के विकास के लिए उतना ही महत्व है जितना एक पीछे के विकास के लिए उपजाऊ भूमि एवं अनुकूल जलवायु का।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भौगोलिक दृष्टिकोण (The Geographical Approaches towards International Affairs)

प्रायः के कुछ दशकों पूर्व भूगोल को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अतिगण्य महत्त्व दिया जाता था। 'भौगोलिक राजनीति' (Geo-Politics) शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन् 1916 में रुडोल्फ़ जैलिन (Rudolf Kjellén) द्वारा किया गया जिसने अपनी पुस्तक 'The State as a Form of Life' में बतलाया कि भौगोलिक राजनीति राज्य की वह विचारधारा है जो उसे एक भौगोलिक साधनवी मानती है। पेंडलफोर्ड और लिफ़न के अनुसार भौगोलिक राजनीति, विज्ञान तथा राजनीति के क्षेत्र को जोड़ने का एक प्रयास है। यह भौगोलिक सम्बन्धों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय हित और रणनीति के रूप में मूलपाँक्ति करने का प्रयास करती है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सन्दर्भ में 19वीं 20वीं शताब्दी के कुछ प्रमुख भूगोल-शास्त्रियों और राजनीतिज्ञों रोचक दृष्टिकोण जान लेना उन्मुक्त होगा। इन दृष्टिकोणों से हम स्पष्टतः पता लग सकेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भूगोल को कितना महत्त्व दिया जाता रहा है।

1 मैकइंडर के विचार (The Ideas of Mackinder)—भौगोलिक राजनीति के आधुनिक विचारों के विकास का श्रेय सर हार्फर्ड मैकइंडर (Sir Halford Mackinder) को दिया जाता है जो इंग्लैण्ड के भूगोल-शास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने दुनिया की भूमियों की कुछ भौगोलिक विशेषताओं का विवृत्त-पूर्ण विश्लेषण किया और समुद्रों से उनका सम्बन्ध दर्शाते हुए बताया कि कुछ भौगोलिक वास्तविकताएँ भावी विश्व की घटनाओं के विकास को मोड़ने में महत्त्वपूर्ण कार्य करेंगी। मैकइंडर ने अपने विचार सर्वप्रथम सन् 1904 में प्रतिपादित किए और

इनको सन् 1919 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'प्रजातन्त्रात्मक आदर्श और यथार्थ' (Democratic Ideals and Realities) में परिवर्तित किया तथा सन् 1943 में उनको पुनः सम्पादित किया।

मैकाइडर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को विश्व द्वीपों के रूप में वर्गीकृत किया। उन्होंने यूरेशिया के आन्तरिक क्षेत्र को इस प्रदेश की केन्द्रीय भूमि (Heart Land) बताया। यह पश्चिम जर्मनी से आरम्भ होकर सोवियत यूरोप में होता हुआ केन्द्रीय साइबेरिया तक पहुँचा है। उन्होंने विश्व के अन्य भागों को भी आन्तरिक त्रिसैंट (Inner Crescent), रिमलैण्ड (Rim Land), व बाहरी त्रिसैंट (Outer Crescent), आदि शीर्षकों से वर्गीकृत किया तथा उनकी अलग-अलग विशेषताओं एवं प्रभावों का वर्णन किया। मैकाइडर का विश्वास था कि समुद्र-शक्ति का प्रभाव-शाली युग समाप्त होने को है। उनका कहना था कि फँक कर मारे जाने वाले शास्त्रों के आविष्कार से पूर्वी यूरेशियन मुख्य भूमि आक्रमणों से अपेक्षावृत मुक्त रहेगी और क्योंकि इस भूमि में प्राकृतिक साधन और मनुष्य-शक्ति की अधिकता है इसलिए यह महान् शक्ति प्राप्त करने में सक्षम है। मैकाइडर का तर्क था कि यदि अन्य चीजें समान हैं तो मुख्य भूमि (Heart Land) दुनिया का मुख्य क्षेत्र बन जाता है। उनका कहना था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वही मुख्य भूमि (Heart Land) पर अधिकार रखता है और जो मध्य भूमि पर शासन करता है वह विश्व द्वीप पर अधिकार रखता है और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह ससार पर अधिकार रखता है।

वार्सा के शांति-सम्मेलन के दौरान मैकाइडर ने यह चेतावनी दी थी कि जर्मनी पुनः यूरोपीय रूस पर अधिकार कर मुख्य भूमि पर नियन्त्रण कर सकता है। सन् 1943 में उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि रूस जर्मनी पर अधिकार कर लेता है तो वह आन्तरिक त्रिसैंट को जीन सकता है और उसके बाद विश्व-साम्राज्य बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। यह डर उस समय और अधिक बढ़ गया जब द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लाल सेनाप्री ने केन्द्रीय यूरोप और पूर्वी जर्मनी पर अधिकार कर लिया। जब चंकोम्बोवाकिया में फरवरी सन् 1948 में साम्यवादी आन्ति हो गई तो पश्चिमी यूरोप के देश कनाडा, संयुक्तराज्य अमेरिका आदि ने नाटो सन्धि सम्पन्न की। ट्रूमैन-प्रशासन की सन्धियों की नीति, ट्रूमैन सिद्धान्त, नाटो, सिएटो और सेंटो आदि सन्धियाँ मैकाइडर के विश्लेषण के आधार पर ही संचालित हो रही थी ताकि रिमलैण्ड की मुख्य भूमि को शक्ति द्वारा प्रशासित होने से रोका जा सके।

विश्व की घटनाओं को देखने तथा उनका अनुमान लगाने की दृष्टि से मैकाइडर के विचार पर्याप्त उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण हैं। इस आधार पर किसी भी देश की सम्भावित सामर्थ्य को आँका जा सकता है। मैकाइडर के विश्लेषण के आधार पर ही महाशक्तियाँ यूरोप से एशिया की ओर बढ़ रही हैं। यदि सोवियत संघ और चीन एक साथ मिलकर कार्य कर रहे होते तो शायद मैकाइडर की भविष्यवाणी पूरी हो गई होती। मैकाइडर का विचार मुख्यतः यूरोप से प्रभावित था और उन्होंने अमेरिका को

एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं आता। बाद में उन्होंने उत्तरी अटलांटिक मुख्य भूमि के विकास को पहचाना और उसके विश्लेषण को केवल अभिलेख मात्र नहीं बना सकता।

2 समुद्री शक्ति पर माहन के विचार (The Ideas of Mahan on Sea Power)—माहन ने भी एक विद्वतापूर्ण भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है और समुद्र की शक्ति के महत्त्व पर जोर डाला है। माहन का दृष्टिकोण मॅकाइण्डर के दृग विचार से भिन्न है कि समुद्री शक्ति का महत्त्व घट रहा है। वैसे तो डा दोनों ही विचारकों ने यह कल्पना नहीं की थी कि भूमि, समुद्र, वायु और प्रक्षेपास्त्रों की शक्ति को एक ही सैनिक शक्ति में एकीकृत किया जा सकता है। माहन के विचार इस मान्यता पर आधारित थे कि यूरोप या एशिया की कोई भी महाद्वीपीय शक्ति ब्रिटेन या अमेरिका के नौ-सैनिक नेतृत्व को सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दे सकती। माहन का विश्वास था कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पड़ोसी फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे शक्तिशाली देश हों और वह समुद्री का नियन्त्रण कर सके। ग्रेट-ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी सीमाएँ नहीं हैं जिनकी रक्षा कर। इसलिए वे बड़ी नौ-सेना की स्थापना पर अपने सुरक्षा-कार्यों को केन्द्रित कर सकते हैं। माहन का विश्वास था कि समुद्र पर ही बड़े शक्ति-युद्धों का निर्णय होता है। उसकी मान्यता थी कि ब्रिटेन अपनी नौ-सैनिक सर्वोच्चता को स्थायी रूप से बनाए नहीं रख सकता, इसलिए संयुक्तराज्य अमेरिका को चाहिए कि बड़ी नौ-सेना का संगठन करे ताकि वह बाह्य युद्धों में भाग ले सके। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट माहन के विचारों में रुचि लेते थे, किन्तु संयुक्तराज्य अमेरिका की नीति इन विचारों पर आधारित नहीं थी। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में जो विजय प्राप्त हुई वह संयुक्तराज्य अमेरिका और ब्रिटेन की कुशल नौ-सेना पर आधारित थी जो अपने देश से दूरस्थ स्थानों पर लड़ने में सक्षम थी। आधुनिककालीन विकासों ने माहन के विचारों को कई दृष्टियों से सीमित कर दिया है। हवाई जहाज, अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र आधुनिक औद्योगीकरण आदि के कारण माहन की कई मान्यताएँ महत्वहीन बन गई हैं। माहन के विचारानुसार महाशक्ति के बनने के लिए एक देश को ऐसी सैनिक शक्ति का निर्माण करना चाहिए जो अपने देश से बाहर लड़ाई लड़ सके। यदि माहन ने वायु सेना और भूमि-सेना को भी अपने विचारों में स्थान दे दिया होता तो उनका महत्त्व बढ़ जाता। माहन के विचारों का आज की दुनिया में प्रभाव ग्रेट-ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका की नीतियों द्वारा ही प्रकट नहीं होना वरन् द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी और जापान की शक्तिशाली नौ-सेना और वायु-सेना और सन् 1947 के बाद से सोवियत संघ की जल-सेना एवं वायु-सेना के विकास उसके विचारों की उपयुक्तता को सिद्ध करते हैं। यदि माहन ने आज की परिस्थितियों में लिखा होता तो वह भल एवं वायु-सेना पर अधिक जोर देता।

3. स्पाइकमैन के विचार (The Ideas of Spykman)—प्रोफेसर स्पाइकमैन (सन् 1893-1943) का मुख्य उद्देश्य दुनिया के भौगोलिक एवं राजनीतिक तत्त्वों

का संयुक्तराज्य अमेरिका की रणनीति की स्थिति एवं विदेश-नीति से सम्बन्ध ज्ञात करना था। उनके विचारों में वायु एवं प्रक्षेपास्त्रों के रणनीति सम्बन्धी महत्त्व को ध्यान में रखा गया है। स्पाइकमैन के मतानुसार विदेश-नीति की रचना में भूगोल सर्वाधिक मौलिक रूप से प्रभावी तत्त्व है। उन्होंने यह बताया कि एक देश की सापेक्ष शक्ति केवल उसकी सैनिक सामर्थ्य पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि अन्य अनेक तत्त्वों पर आश्रित रहती है जैसे प्रदेश का आकार, सीमाओं की प्रकृति, जनसंख्या, कच्चा माल, आर्थिक और तकनीकी विकास, वित्तीय शक्ति, प्रभावशाली सामाजिक एकता, राजनीतिक स्थायित्व एवं राष्ट्रीय भावना, आदि। जिस समय संयुक्तराज्य अमेरिका पृथक्ता की नीति को अपना रहा था उस समय स्पाइकमैन ने इस बात पर जोर दिया कि यदि संयुक्तराज्य अमेरिका विश्व-शक्ति में सन्तुलन की स्थापना के लिए ब्रिटेन के साथ सहयोग करके अपनी क्षमता को प्रयुक्त नहीं करेगा तो पुरानी विश्व-शक्तियाँ नए विश्व को घेरने के लिए संगठित हो सकती हैं। स्पाइकमैन के विचारानुसार अमेरिका की नीति प्रभावशाली शक्तियों को यूरोप के महाद्वीपीय रिमलैण्ड में स्थापित होने से रोकने की थी। यदि यूरोप, मध्यपूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया और सुदूरपूर्व रिमलैण्ड में से किसी भी क्षेत्र में कोई विरोधी महाशक्ति विकसित हो गई तो वह संयुक्तराज्य अमेरिका के हितों के लिए एक चुनौती बन जाएगी। संयुक्तराज्य अमेरिका और ग्रेट-ब्रिटेन के पास पर्याप्त नौ-सेना है। यदि ये दोनों मित्र बन गए तो उस प्रदेश पर नियन्त्रण स्थापित कर सकने हैं जिसे मैकाइण्डर ने आन्तरिक क्रीसेट कहा था और स्पाइकमैन उसे रिमलैण्ड कहते हैं। स्पाइकमैन का विचार है कि जो रिमलैण्ड पर नियन्त्रण करता है वह यूरेशिया पर शासन करता है और जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व पर नियन्त्रण करता है। स्पाइकमैन के अध्ययन का उद्देश्य यह नहीं था कि संयुक्तराज्य अमेरिका दुनिया पर शासन करे। वह विश्व में शान्ति चाहते थे और इसके लिए यूरेशिया के अन्तर्गत शक्ति-सन्तुलन को आवश्यक समझते थे। स्पाइकमैन के समय से ही यह स्पष्ट हो गया है कि प्रत्येक स्थानीय शक्ति-सन्तुलन विश्व-शक्ति-सन्तुलन के अधीनस्थ होता है और संयुक्तराज्य अमेरिका की शक्ति किसी भी शक्ति-सन्तुलन के लिए परमावश्यक है।

4. हाशोफर के विचार (The Ideas of Haushofer)—जर्मनी के भूगोल-शास्त्री वाल्टर हाशोफर (सन् 1869-1946) ने भौगोलिक राजनीति पर बहुत कुछ लिखा है। उसका नाजी विचारों पर बहुत प्रभाव था। हाशोफर तथा उसके अनुयायियों के मतानुसार भौगोलिक-राजनीति एक गुप्त वस्तु थी जो जेल्लेन (Kjellen) के इस विचार पर आधारित थी कि राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण है तथा शक्ति राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। इस आधार पर हाशोफर ने यह बताया कि जर्मनी-निवासियों की उच्च जाति के रहने के लिए पृथक् क्षेत्र की आवश्यकता है। इसे भौतिक श्रोतों की दृष्टि से आरम्भ-निर्भर होना चाहिए तथा यूरोपीय मुख्य भूमि या नियन्त्रण करना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के मार्ग में ग्रेट-ब्रिटेन की नौ-शक्ति

एवं सोवियत संघ की चल-सेना बाधक थी, अतः जर्मनी के सामने युद्ध करने के अलावा और कोई रास्ता न था। नाजी पार्टी की हार के साथ ही हाशेफर के विचारों का प्रभाव भी समाप्त हो गया। संशेप में उसने नाजी आक्रमण या भ्रमर्यन करने के लिए भूमि-प्रसार की विचारधारा का पक्ष लिया तथा भौगोलिक राजनीति के विश्लेषण की प्रवहेलना की।

5 भूगोल पर साम्यवादी विचार (Communist Ideas on Geography)— साम्यवादी पद्धति पूर्ण शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करती है, किन्तु साम्यवादी लेखकों द्वारा कही भी भौगोलिक राजनीति के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके विपरीत उनका विश्वास इतिहास के विकास की द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया में है तथा वे मजदूरों की वर्ग-युद्ध जीतने की योग्यता में विश्वास करते हैं। साम्यवादी नेतृत्व भूगोल की रणनीति के दृष्टिकोण से व्याख्या करता है। द्वितीय विश्व-युद्ध के द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का साम्यवादी रूस ने प्रयोग किया और पूर्वी यूरोप में प्रभावित राज्यों की स्थापना की। इसके अतिरिक्त टर्की के दरें में, उत्तरी ईरान में, बोर्नम द्वीप में तथा वॉन्स्टक में भी इसने अपने पाँव जमाने का प्रयास किया, किन्तु सफलता प्राप्त न हो सकी। इसी प्रकार साम्यवादी चीन भी दक्षिण एवं दक्षिणपूर्व एशिया में पैर फैलाता जा रहा है तथा इन क्षेत्रों से साम्राज्यवादी शक्तियों के हटने की निरन्तर माँग करता रहता है। वह भारत के कुछ भाग पर तथा सोवियत संघ के मध्य एशिया के कुछ प्रदेश पर दावा कर रहा है। यह कहा जाता है कि साम्यवाद को पेरिस से पेरिस पहुँचने के लिए जो रास्ता अपनाना होगा वह है यूरेशियन रिमलैण्ड (Eurasian Rimland) का। यदि इस मार्ग में अफ्रीका या संयुक्तराज्य अमेरिका ने टाँग फँसाई तो साम्यवाद की विजय लम्बी पड़ सकती है। सन् 1945 में जापान के आत्म-समर्पण की वर्षगांठ के अवसर पर साम्यवादी चीन के उप-प्रधानमंत्री लिन पियाओ (Lin Piao) ने साम्यवादी विश्व-विजय की राजनीति की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसमें भौगोलिक रणनीति के कुछ तत्वों को स्थान दिया गया था। यह बताया जाता है कि चीन में माओत्सेतुंग की साम्यवादी विजय की राजनीति की सफलता का कारण यह था कि उसने देहाती क्षेत्रों को शान्ति का आधार बनाया था और बाद में शहरों की भी घेराबन्दी की थी। इसी नीति को विश्व में साम्यवादी शान्ति लाते समय काम में लाया जा सकता है। चीनी नेताओं के मतानुसार यदि हम सम्पूर्ण विश्व पर विचार करें तो उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप को 'दुनिया के नगर' माना जा सकता है तथा एशिया, अफ्रीका एवं लेटिन अमेरिका को दुनिया के देहाती क्षेत्र कह सकते हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के पूँजीवादी देशों में मजदूरों का शान्तिकारी आन्दोलन कई कारणों से मन्द पड़ गया है जबकि एशिया, अफ्रीका एवं लेटिन अमेरिका में जन-आन्दोलन व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार साम्यवादी विचारकों के मतानुसार विश्व का वर्तमान स्वरूप वह है जिसमें शहरों के चारों ओर देहाती क्षेत्रों का घेरा पड़ा हुआ है। देहाती क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है और वे ही विश्व में शान्ति ला सकते हैं।

इस प्रकार चीन के नेता भौगोलिक राजनीति को एक विशेष रूप में अपनाते हैं। उनकी दुनिया की तस्वीर अलग है और जब तक उसको नहीं समझा जाता तब तक साम्यवादी देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को सही रूप में समझना कठिन होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल का प्रभाव

(The Influence of Geography upon

International Politics)

वर्तमान काल में अधिकांश भूगोल-शास्त्री भूगोल की सापेक्षता के सम्बन्ध में पर्याप्त सजग हैं तथा यह मानते हैं कि भूगोल कोई निर्णायक तत्त्व नहीं है वरन् यह राज्य-व्यवहार को स्वरूप प्रदान करने वाले कई तत्त्वों में से एक है। भूगोल का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना प्रभाव है यह जानने के लिए पी ई जेम्स (P. E. James) का यह पर्याप्त उपयोगी प्रतीत होता है कि धरती का भौतिक स्वरूप अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ रखता है अर्थात् व्यक्ति के लिए भौतिक वातावरण का क्या महत्त्व है यह तय करना उसके स्वयं के दृष्टिकोण, तकनीकी योग्यता एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है। मानव-संस्कृति के इन तत्त्वों में से किसी में भी परिवर्तन होने पर धरती द्वारा प्रदत्त आधार का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस प्रकार शक्ति के तत्त्व के रूप में भूगोल का महत्त्व सापेक्ष है, किन्तु इस तथ्य से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल का प्रभाव कम नहीं हो जाता क्योंकि शक्ति के प्रायः सभी तत्वों का महत्त्व सापेक्ष है। यह सच है कि भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या, वातावरण एवं उद्योग आदि के आँकड़ों के उल्लेख मात्र का कोई महत्त्व नहीं है जब तक कि इसे मनुष्य द्वारा प्रयोग के उद्देश्य के प्रसंग में न देखा जाए जिसके लिए कि मनुष्य अपने वातावरण को अलग-अलग रूप से देखने और नियन्त्रित करने की क्षमता रखता है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भूगोल का सम्बन्ध भी बदलता रहता है अर्थात् स्पष्ट रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि क्या भूगोल का रूप एक देश के लिए उपयुक्त रहेगा तथा उसकी शक्ति को बढ़ाने का साधन होगा तथा किस प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ उसकी शक्तियों को कम कर देंगी।

भौगोलिक तत्त्व पर विचार करते समय उसकी सापेक्षता को तो ध्यान में रखना ही चाहिए, किन्तु साथ ही यह तथ्य भी जान लेना चाहिए कि भूगोल राष्ट्रीय शक्ति एवं रणनीति से अनेक विशेष रूपों में सम्बन्ध रखता है। एक के बाद एक होने वाले तकनीकी विवाहों के कारण विश्व में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं, किन्तु इनसे स्थिति, जलवायु, आकार एवं मानचित्र का महत्त्व कम नहीं होता है। स्टीफेन बी जोन्स (Stephen B. Jones) ने सुझाया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल के प्रभाव को दो दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए—प्रथम, गत्यात्मक पदार्थों की विस्तृत सूची (Inventory) और दूसरी 'रणनीति' (Strategy)। जोन्स के मतानुसार इन्वेंट्री शब्द एक देश की उस सम्भावित शक्ति को इंगित करता है जो उसके आकार, जनसंख्या, साधन-स्रोत एवं औद्योगिक आधार के कारण उसे प्राप्त होनी है। इसमें आधार एवं विकास का अधिष्ठित सम्मिश्रण होना है। यह शक्ति

उत्पादिन वस्तुओं के प्रकार के आधार पर अनेक रूपों वाली हो सकती है। इसके अनिश्चित उत्पादिन वस्तुओं का वितरण इस प्रकार किया जाए कि व्यय की अधिक से अधिक मात्रा सैनिक सामान में लगे। स्विट्जरलैंड में प्राकृतिक साधन पर्याप्त हैं, उनको प्रयुक्त करने के साधनों की भी कमी नहीं है, किन्तु फिर भी वहाँ ये सब चीजें लोगों के जीवन-स्तर को जैसा उठाने में ही सहयोग कर सकती हैं। दूसरी ओर संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत संघ के पास पर्याप्त प्राथिक आधार है जिन पर शक्ति अन्तिम रूप से प्राप्ति रहती है। 'रएनीनि' उन उतकृन्तों की ओर संकेत करती है जो भौगोलिक स्थिति को तकनीक से मिटा देने पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रभुत्व स्थापित करने से उत्पन्न होती है।

यदि हम पिछली शताब्दी के ऐतिहासिक अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो इन्वेंट्री तथा रएनीनि के मध्य स्थित अन्तर का विरलेपरात्मक मूल्य स्पष्ट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में जर्मनी के एकीकरण एवं द्रुतगति में होने वाले औद्योगिक विकास ने उसकी प्राथिक, जनसह्य-सम्बन्धी एवं औद्योगिक इन्वेंट्री को व्यापक रूप से बढ़ा दिया। इसके फलस्वरूप जर्मनी इस भाषा और विश्वास के साथ दो बार विश्व-युद्ध में उलझा कि इसके कारण उसे यूरोप में प्रभुत्व प्राप्त हो जाएगा। रएनीनि की दृष्टि से जर्मनी के एकीकरण एवं औद्योगिकरण ने उसे भौगोलिक विघटन की स्थिति के दुष्परिणामों से मुक्त कर केन्द्रीकृत शक्ति के लाभों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान की। एक देश के अस्तित्व पर स्थान (Location) के रएनीनि सम्बन्धी परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके लिए अन्य उदाहरण स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम प्रादि देगों के हैं। बेल्जियम की स्थिति तीन बड़ी शक्तियों—फ्रेड-ब्रिटेन, फ्रांस एवं जर्मनी के लिए रएनीनि की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है, अतः वह चाहते हुए भी निष्पक्ष (Neutral) नहीं रह सकता। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की स्थिति ऐसी है कि इसका पश्चिमी यूरोप की इन बड़ी शक्तियों के लिए रएनीनत्व की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। यही कारण है कि यह देश अपने आपको दो विश्व-युद्धों से बचाए रख सका।

कनाडा एवं लेटिन अमेरिका के गणराज्यों में कुछ समय पूर्व तक न तो पर्याप्त जनसह्य थी और न ही औद्योगिक आधार, ताकि इनको बड़ी शक्ति कहा जा सके। ये देश भौगोलिक रूप में शक्ति के मुख्य केन्द्रों से दूर थे और इसलिए वे आक्रमणों से सुरक्षित रहे। संयुक्तराज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ को सर्वोच्च शक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्पत्ति की उपयुक्त इन्वेंट्री एवं एक रएनीनियुक्त स्थित-दोनों ही भौगोलिक लाभों का उपयोग करते हैं। इन लाभों के परिणामस्वरूप ही एक गतःशब्दों पूर्व डी. टॉकविच ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन रूस और अमेरिका आपसे दुनिया के भाग्य निर्माता बन जाएंगे। मंकाइण्डर ने यद्यपि विश्व के आधुनिक विकासों के बारे में नहीं सोचा था और न ही इनकी कल्पना की थी, किन्तु भौगोलिक आधार पर अध्ययन करने के बाद उसने जो निष्कर्ष निकाले वे आज भी सही हैं और उसने संसार के जिन क्षेत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया था उनमें से कई-एक अब भी संघर्ष के केन्द्र हैं।

मध्यपूर्व एवं एशिया के जलवायु पर राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि की दृष्टि से कभी विचार नहीं किया गया जैसा कि यूरोप में किया गया है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जनसंख्या की समस्या भी अधिक है, इसलिए अरब एवं एशिया के राष्ट्र अपने स्रोतों का विकास नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप ये क्षेत्र शक्ति के केन्द्र रहने की अपेक्षा शक्ति से शून्य रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल के महत्व के सम्बन्ध में मेकलेलन एवं अन्य का यह कथन उचित ही है कि भूगोल वह नींव स्थापित करती है जिस पर कि सामर्थ्य, पारस्परिक निर्भरता एवं सघर्ष निर्भर रहते हैं। इसके महत्व को कम नहीं आँका जाना चाहिए।

प्राकृतिक साधन (Natural Resources)

राष्ट्रीय शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व प्राकृतिक साधन है। प्राकृतिक साधन राष्ट्र की पूँजी होते हैं परन्तु कोई भी प्राकृतिक साधन उस समय तक राष्ट्र की पूँजी नहीं कहा जा सकता जब तक कि राष्ट्र उसका उचित उपयोग करना न जानता हो। सम्भावित (Potential) और वास्तविक (Actual) प्राकृतिक स्रोत में भी अन्तर करना आवश्यक है क्योंकि वास्तविक स्रोत ही दरअसल एक देश को शक्ति प्रदान करते हैं। पर सम्भावित स्रोत महत्वहीन नहीं होते और कभी-कभी तो उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है जितना कि वास्तविक स्रोतों का।

हामर एवं परकिंस ने प्राकृतिक स्रोतों के इन रूपों का उल्लेख किया है—कच्चा माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक शक्ति के साधन, खाद्य-पदार्थ तथा कृषि-उत्पादन। श्लीचर ने इन स्रोतों के तीन प्रकारों का उल्लेख किया है—खाद्यान्न, निर्माणालम्बक सामान (Construction Materials) एवं शक्ति-उत्पादक (Energy Producers)। हंस मॉर्गन्थो ने प्राकृतिक साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया है—प्रथम, खाद्यान्न (Food) और द्वितीय, कच्चा माल (Raw Material)। यह वर्गीकरण सरल भी है और इसमें प्राकृतिक साधनों के सभी रूप आ जाते हैं। कच्चे माल के तीन भाग किए जा सकते हैं—खनिज पदार्थ, वानस्पतिक उत्पादन और पशुओं द्वारा उत्पादित कच्चा माल। खनिज पदार्थों में कोयला, पेट्रोल, लोहा, ताँबा, जस्ता, टिन, मैंगनीज आदि की गणना होती है। वानस्पतिक उत्पादनों में कपास, रबर, दौंस, नारियल, आदि सम्मिलित हैं। इनमें से तत्त्व भी शामिल हैं जिनसे दवाइयाँ, रंग, वार्निश आदि बनाई जाती हैं। पशुओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं में दूध, घण्डे, गोشت, रेशम, ऊन आदि का नाम लिया जा सकता है।

खाद्यान्न

यह राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्त्व अथवा उप-तत्त्व है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में कहावत प्रसिद्ध है कि 'सेनाएँ अपने उदरों पर यात्रा करती हैं' (Armies travel on their stomach) अर्थात् सैनिक भूखे पेट रह कर नहीं लड़ सकते। प्राचीन काल में दुश्मन किले की घेर लेते थे, रसद-मार्ग बन्द कर देते थे और विजय प्राप्त करते थे। स्थानीय स्तर की ये चालें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू की जा

सकती हैं। द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी को अपनी जीवन-रक्षा के लिए तीन प्रकार की नीतियों को व्यवहार में लाना पड़ता था—(क) खाद्यान्न समाप्त होने से पूर्व ही शोध विजय प्राप्त कर एक लम्बे युद्ध से बचना, (ख) पूर्वी यूरोप के अधिक धन-उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार जमा लेना, एवं (ग) ब्रिटिश नौ-शक्ति का विनाश ताकि वह जर्मनी के उन मार्गों को प्रवरद्ध न कर सके जिनसे वह खाद्यान्न आयात करता था। वास्तव में ब्रिटिश और जर्मनी की खाद्यान्न-निर्भरता उनकी बहुत बड़ी कमजोरी रही। जर्मनी तो खाद्यान्न में आत्म-निर्भर रहने के लिए विजित प्रदेशों की जनता को भूखा तक रखता था अथवा भारी सख्या में लोगों को मार देता था। खाद्य-मोर्चे पर भारत की कमजोरी ने हमारी विदेश-नीति को किस तरह प्रभावित किया है, कहने की आवश्यकता नहीं।

मॉर्गेंथो के इस दृष्टिकोण से असहमत होना कठिन है कि अनाज की दृष्टि से आत्म-निर्भर राष्ट्र उस राष्ट्र की तुलना में अनेक दृष्टियों से श्रेष्ठ है जो अनाज का आयात करते हैं, स्वयं नहीं उगा पाते या भूखों मरते हैं। जब तक देश अन्न की दृष्टि से आत्म-निर्भर नहीं हो जाता तब तक उस देश को महान् शक्ति का स्तर प्रदान नहीं किया जा सकता और यदि वह अन्न की दृष्टि से लगातार अभावग्रस्त बना रहा तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लगातार कमजोर बना रहेगा। किसी भी देश में अनाज की अभावग्रस्त अवस्था के मुख्य पहलू होते हैं—उस देश की निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या-वृद्धि के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन की कमी, विदेशों से आयात के अवसरों की कमी या उन वस्तुओं का निर्यात न हो पाना जिनके बदले अनाज आयात किया जा सकता है, आदि। इसमें कोई सन्देह नहीं कि खाद्यान्न का अभाव समूचे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। खाद्यान्न से पीड़ित लोग कार्य करने में असमर्थ होते हैं और साथ ही राष्ट्र के लिए अमान्ति तथा असंतोष-वृद्धि का कारण बन जाते हैं।

कच्चा-माल

पेंडलफोर्ड एवं लिबन ने लिखा है—“आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण के बिना राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना असम्भव है। औद्योगिकीकरण कच्चे माल विशेषतः खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर करता है।” जर्मनी के हरमन गोयर्सिंग का कहना था—“मकब्रन खाने से हमारी सेनाएँ सिर्फ मोटी होती हैं जबकि इस्पात हमको शक्तिशाली बनाता है।” कच्चा माल राष्ट्र की शक्ति को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नीति और विदेशी व्यापार को भी प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, विश्व के सभी देशों में टीन का उपयोग होता है और चांग विश्व इसके लिए मलाया और बोलेविया की ओर देखना है। इन दोनों राष्ट्रों की विदेश-नीति और उनका विदेशी-व्यापार बहुत-कुछ टीन पर आश्रित है। डेनमार्क अधिक स्थिति से सम्पन्न होते हुए भी औद्योगिक शक्ति नहीं बन सका है क्योंकि वहाँ औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक कोयले और अन्य शक्ति-साधनों का अभाव है।

कच्चे माल की दृष्टि से दुनिया के लगभग सभी देश एक दूसरे से भिन्न हैं और न्यूनाधिक रूप में परस्पर आश्रित हैं। केवल सोवियत रूस ही भकेला ऐसा देश है जिसके पास सभी आवश्यक प्राकृतिक साधनों के विपुल भण्डार हैं। अमेरिका भी इस दृष्टि से भाग्यशाली है, लेकिन उसके बहुत से भण्डार अब खाली होने की स्थिति में आ गए हैं और सैनिक दृष्टि से आवश्यक कई पदार्थों के लिए (कोबाल्ट, मैंगनीज, क्रोम, निकल, प्लेटिनम आदि) वह बड़ी सीमा तक दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है। कच्चे माल में तीन चीजें—कोयला, लोहा और पेट्रोल मुख्य होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही वस्तुएँ आधुनिक उद्योग-धन्यो, व्यवसाय और परिवहन का आधार हैं। वही राष्ट्र आर्थिक और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकता है जिसके पास या तो ये खनिज पदार्थ समुचित मात्रा में मौजूद हों या वह अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा इन्हें प्राप्त करने की स्थिति में हो। संयुक्तराज्य अमेरिका के पास कोयले, पेट्रोल और लोहे के सर्वोत्तम भण्डार हैं। रूस के पास भी तेल के विशाल भण्डार हैं और रूमनिया से वह विपुल मात्रा में तेल प्राप्त करने में सफल हुआ है। कोयले और लोहे के भण्डारों की भी उसके पास कोई कमी नहीं है। पेट्रोल या तेल पश्चिमी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र है। इस दृष्टि से अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस आदि देशों ने पश्चिमी एशिया के प्रति जो नीति अपनाई है वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत में 'तेल-राजनय' (Oil-diplomacy) के नाम से विख्यात है। विगत कुछ वर्षों से आणविक शक्ति के विकास के साथ यूरेनियम भी एक महत्वपूर्ण खनिज बन गया है। यूरेनियम के अणु से आणविक शक्ति उत्पन्न होने तथा उस शक्ति की सैनिक उपयोगिता होने के कारण राष्ट्रों की ध्येयियों में अन्तर आ गया है। यूरेनियम ने बर्माडा, रूस, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया आदि की राष्ट्रीय शक्ति को बहुत बढ़ाया है जबकि उसके अनुपात में अन्य देशों की स्थिति में गिरावट आई है।

शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी देश के पास प्राकृतिक साधन वषेष्ठ मात्रा में होने चाहिए। पर्याप्त प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न राष्ट्र शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में केन्द्रीय स्थान प्राप्त कर लेता है क्योंकि दूसरे राष्ट्रों को उसके सहयोग की आवश्यकता होती है और इससे वह उन पर प्रभाव डालने की स्थिति में आ जाता है। दूसरे देशों पर आश्रित रहने वाले राष्ट्र महाशक्ति बनने का केवल स्वप्न ही देख सकते हैं। अनेक खनिज-पदार्थ हाल ही में विवक्षित हुए हैं। कहा जाता है कि मशीनीकृत युद्ध का विकास होने के बाद केवल वे ही देश बड़ी शक्ति बन सकते हैं जिनमें गुणात्मक एवं सख्यात्मक दृष्टि से पर्याप्त बल-कारखाने हैं और खनिज पदार्थों द्वारा ही इन बल-कारखानों की क्षमता निश्चिन्त होती है अतः अप्रत्यक्ष रूप में वे प्रभावशाली सैनिक शक्ति की आवश्यक शक्तें हैं।

जनसंख्या (Population)

श्रीचर का यह अभिमत सही है कि "जब तक उत्पादन और युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी, तब तक यदि अन्य तत्त्व समान रहे तो जिस राज्य के

पास इन दो कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग होंगे, वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान होगा।¹ युद्ध में विजय पाने के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रौद्योगिक साधनों को संचालित करने के लिए मानव-शक्ति नितान्त आवश्यक है। मात्र के स्वचालित मशीनों और हथियारों के युग में भी जनसंख्या के महत्त्व में कोई कमी नहीं आई है। इन्हें संचालित करने, सुधारने, इधर-उधर ले जाने आदि के लिए मनुष्यों के बिना काम नहीं चल सकता।

संख्यात्मक पहलू

राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से जनसंख्या के सख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। अधिक जनसंख्या युद्ध में लड़ने के लिए अधिक सैनिक और उत्पादन-कार्यों के लिए अधिक श्रमिक प्रदान कर सकती है। अधिक जनसंख्या युद्ध और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए योग्यतम व्यक्तियों को छांटने की सुविधा प्रदान करती है। युद्ध काल में अधिक संख्या का ज्ञान सैनिकों के आचरण और मनोबल को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। अधिक जनसंख्या वाला देश अपने प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन करके और अपनी शक्ति पहचान कर जब जाग उठता है तो विश्व-राजनीति में उसकी आवाज की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अधिक जनसंख्या वाला देश जब स्वतन्त्रता के लिए छटपटाने लगता है तो उसे विदेशी नियन्त्रण में नहीं रखा जा सकता। अधिक जनसंख्या वाले देश को आसानी से हड़पा भी नहीं जा सकता। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जबकि आक्रमणकारी राष्ट्र अच्छे नेतृत्व, अच्छे हथियारों और कुशल सैनिकों के होने हुए भी अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र पर विजय प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। पिछली शताब्दी में तो यह आम कहावत थी कि "ईश्वर सदैव बड़ी सैनिक टुकड़ी के पक्ष में रहता है।" हमारे समय में भी कोरिया-युद्ध का इतिहास साधो है कि चीन ने भारी संख्या में सैनिक भेजकर अमेरिका के होसले पस्त कर दिए थे। भारत-चीन युद्ध में भी चीन की विजय एक का मुरर कारण उसकी भारी सैनिक संख्या थी।

उपर्युक्त विश्लेषण का यह अभिप्राय नहीं है कि अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र कम जनसंख्या वाले राष्ट्र से अवश्य ही शक्तिशाली होता है। जनसंख्या के आकार और राष्ट्रीय शक्ति के बीच कोई आवश्यक एवं समान सम्बन्ध नहीं है। जर्मनी, जापान, अमेरिका, रूस आदि की जनसंख्या भारत और चीन की जनसंख्या से बहुत कम है, लेकिन विश्व के आर्थिक और सैनिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्रों में जो स्थान उनका है वह भारत या चीन का नहीं। अरब-राष्ट्रों के गूकाबले इजरायल कम जनसंख्या वाला छोटा-सा देश है, लेकिन सम्पन्नता और शक्ति में वह अरब देशों से बहुत बड़ा-बड़ा है। जनसंख्या की अधिकता की वकालत सामान्यतः इसलिए की जाती है कि कम जनसंख्या वाला देश साधारणतया बड़ी शक्ति नहीं बन सकता, प्रणवाद की बात अलग है। पैडलफोर्ड एवं लिंकन ने भी लिखा है कि यद्यपि

बड़ी जनसंख्या का आशय यह नहीं है कि वह देश अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रभाव डालेगा, लेकिन फिर भी कम जनसंख्या वाले देश अधिक जनसंख्या वाले देशों की तुलना में नुकसान में रहते हैं। आज का साम्यवादी चीन अपनी अपार जन-शक्ति के बल पर ही विश्व की एक बड़ी सैनिक शक्ति बन गया है और रूस तथा अमेरिका जैसी महाशक्तियों के लिए भी चुनौती बना हुआ है।

जनसंख्या की अधिकता कभी-कभी युद्धों और प्रादेशिक विस्तार का कारण बन जाती है। अधिक जनसंख्या को बसाने के लिए राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार करने को बाध्य होते हैं। जर्मनी की विस्तारवादी आकांक्षा के मूल में बड़ा कारण जर्मनी की बढ़ती हुई जनसंख्या का था। वर्तमानकाल में चीन भी अपनी निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या को खपाने के लिए पड़ोसी देशों के भू-क्षेत्रों पर अपनी गिद्ध-दृष्टि जमाए हुए है। पुनश्च, अधिक जनसंख्या के पोषण के लिए यदि राष्ट्र सक्षम नहीं है तो वह जनसंख्या उसके लिए विभिन्न समस्याओं का भ्रम्बार खड़ा कर देती है और राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि का नहीं, कमजोरी का कारण बनती है। यदि देश में प्राकृतिक साधन कम और जनसंख्या अधिक हो तो उसके लिए अपने निवासियों को एक निश्चित न्यूनतम जीवन-स्तर प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा और खाद्यान्न आदि के लिए उसे दूसरे राष्ट्रों पर आश्रित रहना होगा जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि उसकी स्वतन्त्र आवाज नहीं होगी। भारत की विशाल जनसंख्या के सामने जिस प्रकार अन्न संकट हमेशा मुँह बाँध रहा है, वह एक शोचनीय स्थिति है। इस स्थिति के रहते हुए देश की विशाल जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में सहायक न होकर बाधक सिद्ध हो रही है और इसीलिए सरकार विपुल धनराशि परिवार-नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय कर रही है।

गुणात्मक पहलू

जनसंख्या के सख्यात्मक पहलू की विवेचना से ही इसके गुणात्मक पहलू का पर्याप्त स्पष्टीकरण हो जाता है। जनसंख्या की अधिकता का महत्त्व तो है ही, लेकिन राष्ट्र का शक्तिशाली होना वास्तव में जनता की प्रकृति, उसके चरित्र और उसके गुणों पर निर्भर करता है। श्लीचर ने लिखा है कि "यद्यपि युद्ध और शान्ति दोनों ही स्थितियों में जनसंख्या की मात्रा महत्त्वपूर्ण है, लेकिन गुण इससे भी अधिक अपेक्षित हैं।" जनसंख्या की अधिकता को ही शक्ति का प्रतीक मानें तो प्रमथः चीन, भारत, रूस, अमेरिका, जापान, बंगलादेश, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, पश्चिमी जर्मनी, दटली और फ्रांस शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आते हैं, पर राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से यह प्रथम श्रेणी नहीं है। भारत या पाकिस्तान या बंगलादेश या ब्राजील आदि कोई भी राष्ट्र महाशक्ति नहीं है। अकेला रूस या अकेला अमेरिका विश्व के सभी राष्ट्रों से लोहा ले सकता है और सम्भवतः विजय भी पा सकता है। लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या वाले ब्रिटेन का साम्राज्य कभी इतना फैला हुआ था कि उसमें 'सूर्य कभी अस्त नहीं होता था' आशय यह है कि लोगों की संख्या का राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व-रूप में निश्चित ही महत्त्व है लेकिन उनके चरित्र और गुण तुलनात्मक रूप से अधिक अपेक्षित हैं।

राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्त्व के रूप में जनसंख्या का अध्ययन करते समय हमें राष्ट्र के निवासियों की आयु, लिंग, जन्म-दर की गति, जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन-क्षमता, आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि गाँवों और शहरों में लोग किस अनुपात में रहते हैं और उस देश का सामाजिक संगठन कैसा है। द्वितीय महायुद्ध ने जर्मनी और जापान का लगभग पूर्ण विनाश हो कर दिया था, लेकिन अपनी जनता के चरित्र, मनोबल, कार्यक्षमता, प्राविधिक ज्ञान आदि के बल पर इन्होंने न केवल अपना पुनर्निर्माण ही कर लिया है बल्कि आज इनकी गिनती विश्व के चोटी के देशों में है।

लोगों की जाति का भी राष्ट्रीय शक्ति पर भारी असर पड़ता है। एक जाति के लोगों के बीच विचारों की समानता, परम्पराओं की निकटता एवं आपसी मेल-जोल का भाव पाया जाता है। उनकी यह एकता राष्ट्र की शक्ति प्रदान करती है। विभिन्न जातियों और प्रजातियों वाले राज्य में अनेक प्रकार के विवाद उठते रहते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न समस्याएँ पैदा करता है और अल्पमत तथा बहुमत के बीच विवाद देश की शक्ति को क्षीण करने में दीमक का काम करते हैं।

संक्षेप में, राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों में जनसंख्या का अध्ययन करते समय उस राष्ट्र के निवासियों की संख्यामात्र के आधार पर परिणाम निकालने से बचना चाहिए। निवासियों की संख्या के साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि निवासी किस प्रकार के हैं और भविष्य में वे क्या करने की सामर्थ्य तथा आकांक्षा रखते हैं। समाज के स्रोतों और जनसंख्या के आकार के बीच एक सन्तुलन प्रगतिशीलता अपेक्षित है ताकि एक देश अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सके और इस प्रकार महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हो सके। आज की एक गम्भीर समस्या यही है कि जनसंख्या और साधन-स्रोतों के बीच गम्भीर असन्तुलन बढ़ता जा रहा है। अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या को प्रकृति की देन माना जाता है तथा उसे रणनीति की दृष्टि से महत्वहीन बताया जाता है, किन्तु विकसित देशों में जनसंख्या के नियन्त्रण की प्रक्रिया को सफलता के करीब ला दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जनमत का स्थान

एक देश की विदेश-नीति में जनमत द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह इस बात का स्रोत है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जनता का स्थान महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। वैसे भौतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रणेता सदा से ही इतिहास के निर्णायक तत्त्व रहे हैं, किन्तु फिर भी इनका योगदान इतना महान कभी नहीं रहा जितना आधुनिक युग में पाया जाता है। आज का युग मजदूरों की शक्ति का युग कहलाता है जिसमें संसार के अधिकांश भागों को समाजवाद के रंग में रंगना एक उद्देश्य है। इस युग में जनसंख्या का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है तथा कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेते समय जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता।

मजदूर-वर्ग हमारे समय के सामाजिक विकास की एक मुख्य प्रेरक शक्ति है। मानव इतिहास में आज तक जिन वर्गों ने समाज में प्रधानता प्राप्त की है उनमें यह वर्ग सख्या में सभी से अधिक है और प्रायः सभी दलित वर्गों का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। लेनिन ने विश्व में होने वाले किसानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया था कि साम्यवाद की विजय का कारण यह है कि सैकड़ों और हजारों लोग धीरे-धीरे इसके सगर्वक बन गए हैं। यह बहुमत अब जाग्रत हो चुका है तथा कुछ कर गुजरने के लिए आतुर है। इसको मजबूत से मजबूत और शक्तिशाली से शक्तिशाली सत्ताओं द्वारा भी रोका नहीं जा सकता।

मार्क्स और लेनिन के प्रयासों से मजदूर वर्ग में यह पहचानने की शक्ति आ गई है कि उनका हित क्या है तथा वे इसकी साधना किस प्रकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में मजदूर वर्ग के योगदान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में इसके प्रभाव में एक नया विकास यह हुआ है कि विदेश नीतियों का भावात्मक एकीकरण हो गया है। आज युद्ध और शान्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों में जनता की रुचि बढ़नी जा रही है और यह विदेश-नीति के विभिन्न पहलुओं में पर्याप्त रुचि लेती है। इस सबके परिणामस्वरूप विदेश-नीति को जनता की इच्छाओं से प्रभावित होना पड़ता है।

आरबेटोव (Y. Arbatov) जैसे साम्यवादी लेखकों का कहना है कि शोषित मजदूर वर्ग चुनावों में भाग लेता है, इसके अतिरिक्त भी उसके पास कुछ साधन हैं जिनके माध्यम से वह विदेश नीति को प्रभावित कर सके। मजदूर वर्ग का लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं भ्रातृत्व का विकास करना है। मार्क्स द्वारा दुनिया के मजदूरों को एक होने का जो नारा दिया गया उससे साम्यवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि जाहिर होगी है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के बाद ही साम्यवादी क्रान्ति के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। मजदूर-वर्ग के पास हड़ताल आदि के रूप में कई एक शक्तिशाली हथियार हैं जो यदि प्रयुक्त किए जाएं तो पर्याप्त प्रभावशाली साबित हो सकते हैं।

आजकल के युद्ध केवल व्यावसायिक सेनाओं के माध्यम से ही नहीं लड़े जाते। लेनिन के कथनानुसार आज के युद्ध राष्ट्रों द्वारा लड़े जाते हैं। इन युद्धों के संचालन के लिए आवश्यक व्यापक सख्या में जो सेना नियुक्त की जाती है वह मूल रूप से काम करने वाली जनता के बन्धों पर बन्दूक रख कर ही चलती है। जनमहसा का कार्य गृह-स्तर पर भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक सेना का भाग्य उसके भ्रम एवं मनोबल पर निर्भर करता है। यही कारण है कि युद्ध, शान्ति एवं विदेश-नीति के बारे में बहुजनसंरक्षक विचार एक महत्वपूर्ण तत्व बनते जा रहे हैं। इनसे एक देश की सैनिक सान्धर्ष का निश्चय होता है तथा सेना के मनोबल, अपने डिझीजन के गुण एवं गृह-स्तर पर स्थायित्व आदि का निर्धारण होता है। यह कहा जाना है कि निम्न दो विश्व-युद्धों के अनुभव के बाद यह बात उजागर हुई कि युद्धों एवं विदेश-नीति के प्रति जनता का दृष्टिकोण केवल नैतिक तत्त्व तक ही मर्यादित नहीं है।

यह उग वर्ग के शासन को भी समाप्त कर सकता है जो युद्धरत है। यह शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नवीन शक्ति के रूप में उदित हो रही है। इसके फलस्वरूप प्रजातन्त्रात्मक विदेश-नीतियाँ बनने लगी हैं। इस दृष्टि से उपनिवेशों एवं आश्रित देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता मोर्चे हैं उनका भी अपने आप में पर्याप्त महत्त्व है।

यह माना जाना है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जन-साधारण का जो महत्त्व बढ़ा है वह न तो देव योग में हुआ है और न राजनीतिज्ञों एवं कूटनीतिज्ञों के विषयगत गहन आँकलन का परिणाम है। यह विषयगत ऐतिहासिक विकास का प्राकृतिक परिणाम है, यह एक सामाजिक वातावरण है जो मानवता की प्रगतिशील एवं शान्तिवादी शक्तियों का पक्ष है। विदेश-नीति पर जन-साधारण का बढ़ता हुआ प्रभाव प्रतिन्यावादी एवं आक्रमणकारी नीतियों को सकल नहीं होने देना। यह आज की दुनिया की एक अग्रिणीय उपलब्धि है। कोई भी देश इस उपलब्धि को छोड़ना नहीं चाहेगा।

तकनीकी अथवा प्राविधिक ज्ञान (Technology)

तकनीकी अथवा प्राविधिक ज्ञान का कोई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ नहीं है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व के रूप में इसका मूल्यांकन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और शक्ति के अन्य तत्वों के सम्बन्ध में किया जाता है। किंग्सी राइट के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रशिक्षण के रूप में प्राविधिक ज्ञान वह विज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व-राजनीति से संयुक्त करता है। यह यान्त्रिक पद्धतियों के विकास तथा युद्ध-कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा एवं संसार में उनके प्रयोग की कला है।"¹ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले प्राविधिक ज्ञान अथवा तकनीक के रूपों में संचार, औद्योगिक तकनीक, सैनिक तकनीक आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। तकनीक के अन्य रूप भी विश्व-राजनीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य विज्ञान का जनसंख्या के विस्तार पर काफी प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या-नियन्त्रण एवं भोजन की समस्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की मुख्य समस्याएँ बन जाती हैं। तकनीक के जिन दो प्रकारों को भावी विश्व-घटनाओं की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है वे हैं—कृषि एवं जनसंख्या-नियन्त्रण।

जनसंख्या की विशेषताओं तथा भौगोलिक एवं अनेक प्राचिक तत्वों को नक्शों, आँकड़ों और चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि तकनीक का अनुमान हम प्रायः कुछ प्रतीकों के आधार पर लगाते हैं। उदाहरणार्थ, एक प्रतीक यह है कि एक देश विशेष की जनसंख्या का कितना अनुपात कृषि में लगा हुआ है। यदि कृषि-कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है तो यह माना जाएगा कि

कृषि तकनीक बहुत पिछड़ी हुई है और औद्योगिक तकनीक ने भी अपनी पिछड़ी स्थिति के कारण अधिक मजदूरों की माँग नहीं की। दूसरा प्रतीक यह है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन कितना होता है। तीसरा प्रतीक यह माना जा सकता है कि प्रति व्यक्ति शक्ति का व्यय (खपत) कितना है। किसी राज्य के स्तर को मापने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इन सभी प्रतीकों अथवा सूचकों का वर्णन किया जाए या ये सब प्रतीक समान महत्व रखते हों, क्योंकि एक राज्य अपनी प्राथमिकता के आधार पर तकनीक के किसी भी एक पहलू पर अधिक जोर दे सकता है और उस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर एक उच्च स्तर प्राप्त कर लेता है।

तकनीक मानव सम्यता के लिए वरदान है या अभिशाप, यह एक विवादास्पद प्रश्न है जिस पर शायद कभी मतभेद नहीं हो सकता। पर यह निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि तकनीक का राष्ट्रीय शक्ति से गहरा सम्बन्ध है। चिरकाल से तकनीक ने राष्ट्रीय शक्ति की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह माना जाता है कि तकनीक अथवा प्राविधिक ज्ञान की दृष्टि से एक राष्ट्र जितना आगे बढ़ जाता है वह उतना ही अधिक शक्ति की दृष्टि से भी आगे आ जाता है। तकनीक से राष्ट्रीय शक्ति अनेक रूपों में प्रभावित होती है जैसे—यह राष्ट्र के स्वरूप को बदल देती है, इससे राष्ट्रों की शक्ति-स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, राष्ट्र की आक्रमणकारी शक्ति बढ़ जाती है, राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आ जाते हैं, आदि। इन विभिन्न प्रभावों पर कुछ विस्तार से विवेचन अपेक्षित है।

तकनीक द्वारा राष्ट्र के स्वरूप में परिवर्तन

तकनीक राज्य के स्वरूप में परिवर्तन लाने में सक्षम है। आर्नोल्ड टायनबी की मान्यता है कि राजनीतिक समुदाय का आकार संचार-माधनों की प्रगति के अनुपात में विकसित होना है। जब आवागमन के साधन स्थानीय अथवा एकदम अनुसृत थे तब लोग कुछ ही मीलो के दायरे में सामूहिक रूप से रहते थे। कालान्तर में जब लोगों ने घोड़ों आदि का प्रयोग आरम्भ किया तो नगर-राज्य और प्रारम्भिक राज्य की स्थापना हुई। आवागमन के साधनों के विकास के साथ लोग अधिकाधिक क्षेत्रों पर नियन्त्रण करने की और प्रेरित हुए और इस प्रकार के आकार की वृद्धि के साधन के रूप में तकनीकी आविष्कारों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा। 15वीं शताब्दी में जब समुद्रों पर विजय पा ली गई तथा विशालकाय जहाजों का निर्माण हुआ तो अन्तर्महाद्वीपीय साम्राज्य स्थापित हुए और आज ध्वनि की गति से भी लोग्रासी वायुयानों ने दुनिया को एक परिवार का रूप दे दिया है। इसी प्रकार जो समुद्र पहने दो राष्ट्रों के मध्य सम्पर्क बढ़ाने में बाधक थे वे आज सम्पर्क को घनिष्ठ बनाने के साधन बन गए हैं। यह बहने में कोई अत्युक्ति न होगी कि दूरी का भौगोलिक तत्त्व आज बहुत कुछ अंशों में अपना परम्परागत अर्थ खो चुका है। आधुनिक संचार-साधनों के बल पर किसी भी समाचार को विश्व के कोने-कोने में कुछ ही क्षणों में प्रसारित किया जा सकता है। संचार-माधनों और सैनिक संसाधनों के क्षेत्र में तकनीकी खोजों ने शक्ति के नए स्रोत खोज दिए हैं। तकनीकी प्रगति ने उत्पादन के

नए साधन प्रदान किए हैं तथा जनसंख्या-नियन्त्रण के कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाकर राष्ट्र की सामाजिक शक्ति को बढ़ाया है और निवासियों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाया है।

तकनीकी विकास ने राज्यों के केन्द्रीकरण एवं एकता में वृद्धि की है। दुनगामी संचार-माध्यमों के माध्यम से कूटनीतिज्ञ अपने विदेश-कार्यालयों से सीधा सम्पर्क बनाए रख सकते हैं। आज उन्हें नए-नए उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं। इस प्रकार विदेश-नीति-निर्माण का कार्य सरकार में अधिकधिक केन्द्रित हो गया है और दुनिया के प्रत्येक भाग में सरकारी नीति को दूसरे भागों से सम्बन्धित किया जा सकता है। एक उद्युक्त नीति अपनाने के लिए विश्वभर के राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्त्वों को समुक्त कर देखा जा सकता है और अपनाई गई नीति को साकार करने के लिए सैनिक, आर्थिक, प्रचारात्मक एवं कूटनीतिक साधनों का सहारा लिया जा सकता है। संचार-माध्यमों तथा आवागमन के क्षेत्र में तकनीकी प्रसार ने और सैनिक तकनीक के विकास ने घरेलू क्रान्तियों की सम्भावनाओं को कम कर दिया है।

तकनीक द्वारा राष्ट्रों की शक्ति-स्थिति में परिवर्तन

तकनीक अथवा प्राविधिक विज्ञान राज्य की शक्ति-स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। इतिहास साक्षी है कि प्रारम्भ में शक्ति उन देशों के हाथ में थी जो पर्याप्त अस्त्र-शक्ति के स्वामी थे और कृषि-कार्य में उन्नत थे। मध्ययुग में शक्ति का केन्द्र उत्तरी यूरोप, पश्चिमी एशिया, भारत और चीन के कृषि क्षेत्र बन गए। पुनर्जागृति के बाद शक्ति अधिकशतः उन देशों के हाथ में केन्द्रित होती गई जो विशाल जहाजों के देशों के स्वामी थे। बाद में जिन राष्ट्रों ने बन्दूक बनाने की कला पहले सीख ली वे उन राष्ट्रों पर हावी हो गए जो परम्परागत हथियारों से लड़ते थे। समुद्री संचार-व्यवस्था का विकास करके इंग्लैण्ड अनेक दशान्दियों तक विश्व पर छाया रहा और वायु-शक्ति की दौड़ में पिछड़ जाने पर महायुद्ध के बाद ब्रिटेन आदि देशों के स्थान पर अमेरिका एवं रूस प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर आए। आज के अणु और स्पूतनिक युग में तकनीकी ज्ञान राष्ट्र की शक्ति को कितना गरिमामय और प्रभावशाली बनाता है, यह रूस और अमेरिका की प्रगति से स्पष्ट है। कहने का आशय यह है कि तकनीकी विकास युद्ध की पद्धति और राज्यों की शक्ति-स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करता है जिससे शक्ति-सन्तुलन बड़ी शीघ्रता से बदल जाता है। तकनीकी आविष्कारों ने आज छोटे और बड़े राज्यों के शक्ति के अन्तरों को बहुत अधिक बढ़ा दिया है तो दूसरी ओर सभी राज्यों की सुरक्षा की शक्ति को घटा दिया है। तकनीकी विकास की सामान्य प्रवृत्ति देश की सुरक्षात्मक वृद्धि की अपेक्षा आक्रमणकारी शक्ति को बढ़ाने की अधिक रही है। आज सैनिक तकनीक का जो विकास हो चुका है वह विश्व-इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। आज का आशय यह नहीं देखता कि शत्रु की किलेबन्दी कैसी है या उसके सुरक्षात्मक हथियार कितने प्रभावशाली हैं, बल्कि खासतौर पर यह

देखता है कि शत्रु के विरोध की क्षमता कितनी है अर्थात् वह विध्वंस की कितनी जवाबी क्षमता रखता है ।

1. तकनीक द्वारा राष्ट्रों की आक्रमणकारी शक्ति में वृद्धि

ऊपर संकेत दिया जा चुका है कि तकनीक अथवा प्राविधिक विज्ञान से राज्यों की आक्रमणकारी शक्ति में भारी वृद्धि हुई है । तकनीकी हथियारों को अपनाने में पहल करने वाले राष्ट्र उन देशों की अपेक्षा प्रायः लाभ में रहते हैं जो इन शस्त्रों का प्रयोग अथवा सुरक्षात्मक उपयोग बाद में सीखते हैं । युद्ध की तकनीक पर विचार करते हुए मॉर्गेन्थो ने 20वीं शताब्दी की चार महान् नई पद्धतियों की ओर संकेत किया है¹—प्रथम, प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश जहाजों के विरुद्ध विशेष रूप में प्रयोग की गई जर्मनी की पनडुब्बियाँ थी जिनसे यह भय पैदा हो गया कि शायद युद्ध का निर्णय जर्मनी के पक्ष में होगा, किन्तु ग्रेट ब्रिटेन ने उसके जवाब में सशस्त्र-रक्षक जहाजों बेड़े का प्राविधिकार करके पासा पलट दिया । दूसरे, जर्मनी के मुकाबले ब्रिटेन ने प्रथम महायुद्ध के अन्तिम दिनों में टैंकों का भारी सख्या में और मुख्य रूप में प्रयोग किया जिससे मित्रराष्ट्रों की विजय का मार्ग महत्वपूर्ण रूप में प्रशस्त हुआ । तीसरे, जल, धूल और वायु-सेना के युद्ध-संचालन और चातुर्यपूर्ण ब्यूह-रचना के बल पर द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ में जर्मनी और जापान ने चारों ओर तहलका मचा दिया । चौथे, जिन राष्ट्रों के पास अणुशस्त्र और उन्हें फैलाने के साधन हैं वे अपने प्रतिद्वन्द्वियों की तुलना में तकनीकी दृष्टि से बहुत लाभपूर्ण स्थिति में हैं । वास्तव में न केवल तकनीकी प्राविधिकार बल्कि युद्ध-तकनीक भी लड़ाई का नक्शा बदल देती है । जून, 1965 के युद्ध में इजरायल ने आकस्मिक सामूहिक वायु-आक्रमण द्वारा एक ही साथ मिस्र की तीन चौथाई से भी अधिक वायु-शक्ति को धराशायी करके युद्ध विचारदो को स्तम्भित कर दिया था । आज तो अनेक ऐसे जैविक और रासायनिक हथियार तैयार कर लिए गए हैं जिनसे सम्पूर्ण मानव-जाति को ही कुछ घण्टों में नष्ट किया जा सकता है । हैराल्ड तथा मॉर्गेट स्प्राउट ने लिखा है कि बोटुलिनस (Botulinas) नामक विषैले पदार्थ की केवल साढ़े आठ ग्रीस की मात्रा इस धरती पर बसने वाली सम्पूर्ण मानव-जाति को नष्ट कर सकती है ।² स्पष्ट है कि इस प्रकार की तकनीकी प्रगति और सहारक शक्ति के स्वामी राष्ट्रों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि हम उसका सही अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं ।

तकनीक द्वारा राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक अवस्था में परिवर्तन

तकनीकी ज्ञान राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी महायक होता है । यह राष्ट्रीय उत्पादन को सामर्थ्य प्रदान करता है, नागरिकों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महामारियों और मौसमिक बीमारियों से नागरिकों की रक्षा करने में राज्य को समर्थ बनाना है, राष्ट्र की आर्थिक शक्ति और आशामों की वृद्धि करना है । वास्तव में तकनीकी विकास राज्य के छोटे से लेकर बड़े में बड़े

1 *Hans J Morgenthau* : op. cit., pp. 115-16

2 *Harold and Sprout* : Foundations of International Politics, p. 262.

काम में सहायता पहुँचाना है। जनमंशरी और भोजन के अनुपात को तकनीकी प्रगति के बल पर विनियमित किया जा सकता है। तकनीकी ज्ञान ऊर्जा (Energy) को उत्पन्न करने वाला मुख्य तत्त्व है। तकनीक के बल पर ही यह ऊर्जा कोयला, पानी प्राकृतिक गैस, तेल आदि से प्राप्त की जाती है और आज तो अणु-शक्ति भी ऊर्जा के साधन के रूप में अधिकाधिक प्रभावी बनती जा रही है। इस बात की पूरी सम्भावना है कि अणुशक्ति का इन रूपों में समुचित विकास हो जाने पर भविष्य में राष्ट्रों की स्थिति, उनकी सम्पन्नता और उनकी शक्ति के स्तर में व्यापक परिवर्तन आ जाएँगे और यह भी सम्भव है कि आज के बहुत से विपन्न तथा अधिविपन्न राष्ट्र कृषि के शक्तिशाली और सम्पन्न राष्ट्र बन जाएँगे। तकनीकी विकास ने ही विश्वव्यापी आर्थिक सामाजिक सहयोग को इतना बढ़ा दिया है कि हम विश्व को 'एक प्रायिक दुकान' की सजा देने लगे हैं।

तकनीक द्वारा देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता को अर्थपूर्ण बनाना

तकनीकी विकास राजनीतिक स्वतन्त्रता को अर्थपूर्ण बनाता है। स्प्राउट के मतानुसार कोई भी राष्ट्र तकनीकी विज्ञान की दृष्टि से आत्म-निर्भर बन कर ही अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता को अधिक सार्वक और प्रभावशाली बना सकता है तथा स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति का विकास कर सकता है। विश्व-राजनीति का इतिहास यही सिद्ध करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वही राष्ट्र स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय ले पाते हैं जो तकनीकी विकास के लिए दूसरों का मुँह नहीं ताकते। तकनीकी विकास के बल पर राष्ट्र अपनी शक्ति को दूसरे तत्त्वों को भी प्रभावशाली बना लेता है। उदाहरण के लिए, उन्नत और विकसित तकनीक के बल पर कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में आन्ति लाई जा सकती है, सैनिक-शक्ति को सदा में अधिक न होते हुए भी, प्रभावकारी रूप में सफल बनाया जा सकता है और इस प्रकार राजनीतिक स्वतन्त्रता को सही रूप दिया जा सकता है। विश्व के पिछड़े हुए देश, खासतौर पर अफ्रो-एशियाई देश, महाशक्तियों से 'अणु-छद्म' की प्रेरणा इसलिए करते हैं क्योंकि तकनीकी दृष्टि से और साधनहीनता के कारण वे स्वयं की अणु-शक्ति का विकास करने में सक्षम नहीं हैं। यदि भारत भी परमाणु-शक्ति के विकास की दिशा में शीघ्र ही अपने बल-बूते पर खड़ा न हुआ तो भविष्य में उसके परमाणु क्षेत्र में पिछड़ जाने की आशा है। राष्ट्रीय शक्ति का विकास करने के लिए भारत को अपनी परमाणु-नीति में परिवर्तन करना होगा और अपनी तकनीकी सम्पन्नता को कार्यक्रम में परिणत करके एशिया में चीन के नेतृत्व और भय की चुनौती का सामना करना होगा।

तकनीक द्वारा विश्व-सरकार के प्रयासों को प्रभावित करना

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तेजी से बदलती हुई शक्ति-स्थिति जनित राजनीतिक असुरक्षा की भावना, आक्रमण की सामान्य शक्ति और युद्ध में आक्रमणकारी होने के लाभ आदि बातों ने मिलकर शक्ति को नया रूप दे डाला है। तकनीकी विकास ने विश्व को दोराहे पर ला खड़ा किया है। युद्ध-तकनीक के विस्तार से सत्तार को विनाश की ओर ले जाया जाए या प्राविधिक ज्ञान के अधिकाधिक रचनात्मक उपयोग

से मानवता को दुःख और दरिद्रता से छुटकारा दिलाया जाए—यह प्रश्न विवकट है। तकनीकी विज्ञान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि या तो सारा विश्व सहयोग के सूत्र में बँध जाए अथवा सघर्ष का मार्ग अपना कर महायुद्ध का विस्फोट करके समाप्त हो जाए। समय की माँग है कि विश्व के राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अपना विश्वास रखें तथा सामूहिक सुरक्षा के विकास का प्रयास करें। पर चूँकि इस मार्ग को अपनाने में सबसे बड़ी आशंका यह है कि दूसरे राज्य सहयोग न कर सामूहिक सुरक्षा के विकास में बाधक बनेंगे, अतः आवश्यक है कि हम 'विश्व-सरकार' की दिशा में गम्भीरता से सोचें। 'अन्तर्राष्ट्रीयता की घोर दीड़' में ही मानव जाति का भविष्य सुरक्षित है।

तकनीक द्वारा राष्ट्रों की गोपनीयता की समाप्ति

तकनीक अथवा प्राविधिक ज्ञान के विकास ने आज राज्यों के बीच गोपनीयता को बहुत कुछ समाप्त कर दिया है। सैनिक तकनीक को गुप्त रखने के प्रयास आज पहले की भाँति प्रभावशाली नहीं रहे हैं। आज इस प्रकार की नीति विशेष महत्त्व रखती कि अपने देश को तकनीकी मशीनों और अन्य प्राविधिक विधियों के निर्यात पर रोक लगादी जाए। वर्तमान शताब्दी का इतिहास बताता है कि तकनीक की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती। ज्योंही कोई राज्य वैज्ञानिक सफलता प्राप्त करता है त्योंही कुछ अरसे में दूसरे राज्य भी तत्परता से उस वैज्ञानिक सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। अमेरिका ने अणु बम के रहस्य को गुप्त रखा, लेकिन ब्रिटिश और रूसी वैज्ञानिकों ने रहस्य का पता लगा लिया और आज चीन, भारत, फ्रांस, जापान आदि अनेक देश इस रहस्य को समझ चुके हैं।

तकनीक द्वारा शीत-युद्ध को प्रोत्साहन

तकनीकी विकास ने शीतयुद्ध को प्रोत्साहन देकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को और राष्ट्रीय शक्ति के विकास के दाव-पेचों को प्रभावित किया है। अणु-शक्ति-तकनीक के विकास ने ही मुख्य रूप से अमेरिका और रूस के बीच भारी सन्देह जाग्रत करके शीतयुद्ध का विस्तार किया। सैनिक तकनीक से गुटबन्धियों को प्रेरणा मिली और राष्ट्रों में अशान्ति, असुरक्षा की भावना तथा शस्त्र-प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। तकनीक का यह प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सदैव किसी न किसी रूप में कायम रहेगा।

पेंडलफोर्ड एवं लिंकन के अनुसार तकनीकी प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्थापित प्राण विद्वान् पेंडलफोर्ड एवं लिंकन ने किसी राष्ट्र के शेष विश्व के साथ सम्बन्धों पर पड़ने वाले मुख्य तकनीकी प्रभाव को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया है—

प्रथम, तकनीक के कारण एक देश अपनी मान्यताओं और लक्ष्यों में परिवर्तन कर लेता है। संयुक्तराज्य अमेरिका ने जंग समय अपनी पृथक्तावादी नीति को छोड़ा उस समय नई तकनीक के कारण देश की आक्रामक क्षमता बहुत बढ़ चुकी थी। आज तकनीकी ज्ञान ने दुनिया को एक बना दिया है तथापि वह 'एक विश्व' उन

आदर्शवादी स्वप्न-दृष्टियों की कल्पना से भिन्न है जो विश्व-शान्ति के लिए विश्व-सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। आज की दुनिया इस अर्थ में एक है कि संचार-साधनों का विकास हो चुका है, देशों की परस्पर निर्भरता बढ़ चुकी है, अतः संसार के किसी भी भाग में होने वाला छोटा-या सघर्ष भी सब देशों की रुचि का विषय बन जाता है। इस स्थिति में विश्व के राज्य अपने हितों को व्यापक बना लेते हैं और कभी-कभी तो यह व्यापकता सम्पूर्ण पृथ्वी पर विस्तृत हो जाती है। तकनीकी प्रभाव के फलस्वरूप स्थिति यह हो गई है कि एक देश अपनी इच्छाओं को केवल शक्ति के माध्यम से क्रियान्वित नहीं कर सकता और न ही यह सोच सकता है कि पर्याप्त दूरी की समस्याओं का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

दूसरे, तकनीक द्वारा अन्य तत्वों जैसे आर्थिक तत्व, जनसंख्या आदि को भी प्रभावित किया जाता है। उदाहरण के लिए, तेल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को परम्परागत रण-कौशल की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता था, किन्तु अणु-शक्ति का प्रसार हो जाने के बाद इन क्षेत्रों को दी जाने वाली प्राथमिकता घट सकती है। दूरी का भौगोलिक तत्व अपने परम्परागत अर्थ को बहुत-कुछ खो चुका है। जनसंख्या का प्रभाव भी तभी बढ सकता है जब वह तकनीक पर अधिकार रखती है। तकनीकी से सम्पन्न जनसंख्या वाला देश ही महाशक्ति बनने की आकांक्षा रख सकता है।

तीसरे, तकनीक विदेश-नीति को विषय-वस्तु को प्रभावित करती है और इसके द्वारा सम्बंधित कार्यक्रमों पर प्रभाव डालती है। तकनीकी विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किया जाता है, तकनीकी सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, शस्त्रों के नियन्त्रण पर अधिक बल दिया जाता है, बाह्य अन्तरिक्ष तथा संचार-स्थलों को नियमित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास किया है, तकनीक के आदान-प्रदान द्वारा विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, आदि। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले ये विभिन्न कार्य तकनीकी ज्ञान से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं।

चौथे, तकनीक राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन है। यह औद्योगिक देशों को वह सामर्थ्य भी देती है जिसके आधार पर वे सम्पत्ति का प्रचुर निर्माण कर उसका निर्यात कर सकें। यह अर्द्ध-विकसित देशों को पूँजी के उपयोग की सामर्थ्य प्रदान करती है। विभिन्न देश राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करते हैं, इस तरह मानवीय एवं लाभकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय तकनीकी क्रियाएँ सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तरों पर विकसित होनी हैं जिससे राष्ट्र-निर्माण के कार्य को गति मिलती है।

पाँचवें, तकनीक का विदेश-नीति के संचालन के तरीकों पर शान्तिकारी रूप से प्रभाव पड़ा है। पहले के कूटनीतिक तरीके आज असामयिक हो गए हैं। संचार-साधनों पर किया गया प्रचार, तकनीकी सहायता तथा वैज्ञानिक आदान-प्रदान, अन्तरिक्ष एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रम, आदि विदेश-नीति के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

यद्यपि तकनीकी ज्ञान का पर्याप्त भौतिक प्रभाव होता है, तथापि विश्व-राजनीति की घटनाओं के विकास के पीछे इसका कोई मान्य बौद्धिक प्रोचित्य नहीं है। तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं। इसकी स्वयं की कोई अन्तर्राष्ट्रीय सार्यकता नहीं है और इसका मूल्यांकन अर्थशास्त्रीय, सुरक्षात्मक तथा अन्य तत्त्वों के सन्दर्भ में करना होता है। वैसे यह मूल्यांकन अन्तिम रूप से एक राजनीतिक निर्णय होता है। यह पर्याप्त सम्भव है कि राजनीतिज्ञ अपने निर्णय लेते समय तकनीक की पर्याप्त जानकारी से सम्पन्न हो, लेकिन किसी व्यक्ति के एक श्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ होने का यह अर्थ नहीं होता कि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी होगा। आधुनिक तकनीक बड़ी जटिल और व्यय-साध्य है। जो देश इस बोझ और व्यय को वहन करने के लिए तैयार है वही तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।

तकनीकी विकास का आधार

राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होने के कारण तकनीकी विकास सभी देशों के लिए आज जबरदस्त आकर्षण है। सभी राष्ट्र प्रयास करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान का अधिकाधिक प्रयोग कर राष्ट्रीय शक्ति को तेजी से गतिमान बनाया जाए और उच्चता के शिखर पर पहुँचा जाए, लेकिन सभी राज्य आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। इस असफलता का मुख्य कारण देश-विशेष में स्थित सामाजिक परम्पराएँ, सोचने के तरीके, विकास के प्रति लोगों का दृष्टिकोण आदि हैं। हम देखते हैं कि एक ओर रूस और जापान जैसे राष्ट्र हैं जिन्होंने बहुत कम अवधि में आश्चर्यजनक तकनीकी विकास कर लिया है। जापान ने अपने दृष्टिकोण तथा संस्थाओं में बिना कोई भारी परिवर्तन किए ही औद्योगिक एवं सैनिक संगठनों की पश्चिमी तकनीकों को द्रुतगति से अपना लिया है। दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, चीन आदि की स्थिति को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ तकनीकी ज्ञान का प्रसार इतनी तेजी के साथ हुआ है अथवा निकट भविष्य में हो सकता है। विभिन्न राष्ट्रों के उदाहरणों को देखने के उपरान्त तकनीकी विकास के आधार के रूप में हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं—

1. किसी भी देश में होने वाले तकनीकी विवास पर उस देश की सरकार के स्वरूप का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता बर्यात् तकनीकी ज्ञान पश्चिमी देशों का एकाधिकार नहीं है, यह साम्यवादी देशों में भी सम्भव है और अपेक्षाकृत अधिक तेजी से सम्भव है।

2. तकनीकी विवास साम्यवादी व्यवस्था में अधिक तेजी से होगा, यह कोई एकदम ठोस या सत्य विचार नहीं है। रूस के मुकाबले चीन में तकनीकी विकास की गति बड़ी धीमी है।

3. तकनीकी विकास पर सरकार के रूप की अपेक्षा सामाजिक शक्तियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि समाज परिवर्तनशील और विकासशील दृष्टिकोण

ग्रपनाए तो तकनीकी विकास का मार्ग सुगम होगा। इसके विपरीत परम्भवादी और रुढ़िवादी विचारों से ग्रस्त समाज में तकनीकी प्रगति को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में जिस समाज का ढाँचा वैज्ञानिक आधार से मेल नहीं खाता वह समाज पिछड़ जाता है।

साम्यवादी चीन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के मार्ग की जिन प्रमुख बाधाओं का फेयरबैंक ने उल्लेख किया है वे अधिकांश अफ्रो-एशियायी देशों पर लागू होती हैं जिनमें भारत भी सम्मिलित है। ये बाधाएँ मुख्यतया सान हैं—

तर्क पद्धति (System of Logic), चरित्र-चित्रण (Character Writing), सांस्कृतिक शिक्षा (Classical Education), शारीरिक श्रम का विरोध (Aversion of Manual Labour), अर्थ-व्यवस्था पर राज्य का अधिकार (State Monopoly of the Economy), प्रतिशय मनुष्य शक्ति (Abundant Man Power), और शक्तिशाली एवं रुढ़िवादी नौकरशाही (The Powerful and Conservative Bureaucracy)।

प्राविधिक परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

स्त्राउट एवं स्त्राउट ने एक सारिणी प्रस्तुत की है जो समानान्तर रनम्भों में ब्रियत लगभग 300 वर्षों में हुई प्रमुख प्राविधिक प्रगति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं तथा प्रवृत्तियों में से कुछ प्रस्तुत करती है। यहाँ हम विद्वान् लेखकों द्वारा दी गई विस्तृत व्याख्या को प्रस्तुत न कर केवल सारिणी को ही प्रस्तुत कर रहे हैं जो बहुत-सी बातों का स्वतः स्पष्टीकरण करती है, यथा—परस्पर क्रियारत राष्ट्रों के उद्देश्यों और रणनीतियों के सन्दर्भ में नए उपकरण और मशीनों गुविपाएँ वाघ्यनाओं की सीमा बदल देती है, वही आविष्कार दोनों पक्षों की सुविधाओं में वृद्धि या कमी कर सकते हैं, अथवा यह भी हो सकता है कि एक ही आविष्कार से एक का उद्देश्य पूरा हो और दूसरे की हानि हो जाए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में प्राविधिक प्रगति की इस प्रकार की सूची से हम (1) क्षेत्रीय राष्ट्रीय राज्यों की रचना और सुरक्षा-योग्यता, (2) यूरोप के ऐतिहासिक समुद्रपारीय विस्तार, (3) यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों के पूर्ववर्ती संकोच और ध्वंस, (4) हमारे युग में राष्ट्रों में राजनीतिक क्षमताओं का द्वि-प्रवृत्तीकरण, (5) अन्तर्राष्ट्रीय राज्य शिक्षा के संचालन में नए प्रतिरूप आदि के परीक्षण में आगे बढ़ सकते हैं। स्त्राउट महोदय की सूची इस प्रकार है—

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में प्राविधिक प्रगति*

अवधि	अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ	सामान्य रूप से प्रयुक्त आविष्कार
1650 तक	30 वर्षोंय युद्ध की समाप्ति, वेस्टफालिया की सन्धि, आधुनिक यूरोपीय व्यवस्था की रचना ।	समुद्र-वाता के यन्त्र (जुलुबगुला और आदिम ब्रक्षेण गणक यन्त्र) ; महासागर पर यात्रा के लयक जलपोत जो आधी के सात्र भी चल सकें ; डाकप बढत कर मुद्रण ; अपेक्षाकृत अक्षत तोप के डोल प्रहार-प्रक्षेप ; आदिम छोटे आयुध ।
1650-1815	यूरोप मे अनवरत युद्ध-अग्न, अमेरिकी शान्ति फ्रांसीसी शान्ति और नैपोलियनयुगीन युद्ध, विपत्ता की सन्धि ।	वाष्प एञ्जिन, उनका खानो से पवारले भे, सूती वस्त्र-निर्माण और आदिम वाष्प नौकायों मे उपयोग, गतिशील घोडे, जीतने वाला तोपगना, स्टैंडर्ड बिकने बोर वाली मस्कैट आदिम रायफल जैसे छोटे आयुध और तोपखाने के विस्फोटक गोले ।
1815-1914	पश्चिम यूरोप का औद्योगीकरण, अमेरिका और जापान तक औद्योगिक विकास का विस्तार तथा अग्न्यन उमकी शुरुआत, एशिया और अफ्रीका मे यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों का विस्तार, अमेरिका और जापान की बडी शक्ति के रूप मे मान्यता, कई धनीय युद्ध, मिन्तु मोई बडा युद्ध नही ।	खनिज-विज्ञान मे प्रगति बिशेषकर इस्पात निर्माण का विकास ; स्थल-परिवहन मे वाष्प-शक्ति का उपयोग, यूरोप मे रेल-पटरियों का जाल ; उत्तरी अमेरिका और अग्न्यन भी यही सब ; वाष्प टर्बाइन का विकास और तेजदाय्य वायुतरो का ज्ञान, सुघरी हुई पद्धतियों के फलस्वरूप अन्न और कपास आदि की उपज मे वृद्धि ; अर्वापि के प्रतिम दिनों मे रसायन उद्योगो का तेजी से विस्तार जितने वायुमण्डलीय गन्धद्रोजन को स्थिर करना और अति प्रभावकारी रासायनिक विस्फोटकों का विकास शामिल था, विजली, तार, टेलीफोन, जेनरेटर, मोटर, रोशनी, ब्रेतार का तार, भीतरी इवाय वाले एञ्जिन, अनेक उपयोग, मोटरगाडी, पनडुब्बी, विमान आदि, फोजी मारक शक्ति मे अधिक वृद्धि, समुद्री सानें, तारपीनो, शीघ्र प्रहारक तोपें और तोपखाने ।

सम्बन्ध

1914 से

आज तक

प्रत्यक्ष

प्रथम विश्व-युद्ध; रूसी श्रान्ति; फासिस्ट इटली; नाजी जर्मनी और जापान द्वारा उत्तेजित बार-बार संकट; द्वितीय विश्व-युद्ध; औपनिवेशिक साम्राज्यों का 'श्रान्त'; कम्युनिज्म का प्रसार; राष्ट्रों में राजनीतिक क्षमताओं का श्रान्तिकारी पुनर्वितरण; कम्युनिस्ट शक्ति और कम्युनिस्ट विरोधी गठबन्धन के बीच शीत-युद्ध; एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में विशाल राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन ।

सामान्य रूप से प्रयुक्त श्राविका

खनिज विज्ञान में, खासकर फेरो एलाय और हल्की धातु में और विकास; उच्च क्षमतावात् मीटर ईंधन, प्राकृतिक सामग्री के मानवकृत विकल्प-धर्म, पालीमर, प्लास्टिक, आदि । 'चमत्कारपूर्ण' दवाएँ-सल्फा, एंटीबायोटिक एंटी वाइरस टीके, आदि; कड़ी सतह वाली दूरगामी सड़कें; बड़ी मोटर गाड़ियाँ; रेडियो; राडार; डेलीविजन; गतिशील बल्लारबन्द फौजी उपकरण; टैंक आदि; रॉकेट; तोपखाने; विप्लवी नौसेना और (अब तक अग्रयुक्त) रोगाणु आयुध; फौजी नभ शक्ति, मानव शक्ति यान और मिसाइल, आणविक विघटन और फंलाव, ऐटम बम, हाइड्रोजन बम, अणु शक्ति युक्त जलपोत; आदि मानव निर्मित उपग्रह; वायु समुदाय विशेषज्ञता और अन्तर्निष्ठ विज्ञान में अन्य प्रगतियाँ ।

विज्ञान को विदेश-नीति से संयुक्त करने वाले क्रम

स्प्राउट एवं स्प्राउट ने ही अपनी एक अन्य सारिणी में विज्ञान को विदेश-नीति से संयुक्त करने वाले क्रम की सूची प्रस्तुत की है—

विज्ञान को विदेश-नीति से संयुक्त करने वाले क्रम¹

मुख्य क्रम	पृष्ठपोषण करने वाले	शब्दों का अर्थ	और अधिक व्याख्या	
		← अनुसन्धान → (विज्ञान) ← आविष्कार → (प्रविधि)	नए विज्ञान की प्राप्ति उद्देश्यपूर्ति के लिए नए तरीकों की सृष्टि	स्थापना और प्रेक्षण के बीच परस्पर क्रियाकलाप व्यावहारिक विज्ञान और विकास की इंजीनियरिंग
		← नव-संस्कार →	किसी आविष्कार को जनता में लाना	किसी नए उत्पादन, प्रक्रिया या सामाजिक पद्धति का परिचय देना, नवनिर्माण कार्य, औद्योगिक तथा सामाजिक नेतृत्व
		← फैलाव →	विज्ञान और प्रविधि का नए स्थानों या समुदायों में प्रसारण	शिक्षण, प्रशिक्षण, विक्रय, विस्तार-कार्य अन्तर्राष्ट्रीय प्राविधिक सहायता
		← समाज में → परिवर्तन	रिवाजों, संस्थानों, चिन्तन-पद्धतियों में परिवर्तन	नई नीतियाँ, नए कानून, नई सामाजिक आदतें, नई शिक्षा
		← विदेश-नीति →	राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रकाश में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में प्रतिक्रियाएँ	वैज्ञानिक विकास द्वारा प्रभावित और उन्हें प्रचरित करने वाली भी होती है।

- 1 अन्योन्याश्रित सम्बन्ध और पृष्ठपोषक बहुत होते हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धान, विचारों की जलवायु बदल कर सीधे सामाजिक परिवर्तनों को प्रेरणा दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन या अवरोध प्रदान कर सकते हैं अथवा वैज्ञानिकों का ध्यान नए क्षेत्रों की ओर मोड़ सकते हैं। आविष्कार कभी-कभी अनुसन्धान के पूर्वगामी होते हैं।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व के रूप में अच्छे शासन (Good Government as an Independent Requirement of National Power)

इस अध्याय में यद्यपि हमारा मूल उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों के रूप में नृगोल, प्राकृतिक साधन, जनसंख्या और प्राविधिक ज्ञान का विवेचन करना है, तथापि हम राष्ट्रीय शक्ति के एक अन्य महत्वपूर्ण तत्त्व के रूप में अच्छे शासन (Good Government) की उस अवधारणा पर भी संक्षेप में विचार करेंगे जो हंस मॉर्गेन्थो ने प्रस्तुत की है।¹ अन्तर्गतत्वा यह सरकार ही होती है जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों का सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकती है। राज्य तो सम्पूर्ण है, सरकार ही वह मशीन है जो राज्य के विभिन्न कार्यकलापों को, राज्य की इच्छाओं को मूर्त रूप देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में हंस मॉर्गेन्थो ने लिखा है कि सुविचारित कौशलपूर्ण विदेश-नीति भौतिक और मानवीय साधनों की बहुलता पर आधारित होने के बावजूद तब तक अच्छे परिणाम नहीं दिखा सकेगी जब तक कि वह अच्छे शासन पर अवलम्बित नहीं है। मॉर्गेन्थो के मतानुसार राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत के रूप में अच्छे शासन के तीन अर्थ होते हैं।

- (1) राष्ट्रीय शक्ति में योग देने वाले भौतिक और मानवीय साधनों का सन्तुलन,
- (2) इन तत्त्वों का विदेश-नीति के संचालन में सन्तुलन, एवं
- (3) विदेश-नीतियों के पक्ष में जनता का समर्थन।

नीतियों तथा साधनों के सन्तुलन की समस्या

(The Problem of Balance Between
Resources and Policy)

एक अच्छे शासन से अपेक्षित है कि विदेश-नीतियों के लक्ष्यों और साधनों का इस दृष्टिकोण से चयन करें कि इनके समर्थन में प्राप्त शक्ति के आधार पर सफलता की अधिक से अधिक सम्भावना रहे। एक राष्ट्र यदि अपनी दृष्टि बहुत निम्न (too low) रखता है और उन विदेश-नीतियों को छोड़ देता है जो उसकी सामर्थ्य के अन्तर्गत हैं तो वह राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी सही भूमिका भूदा करने में असफल हो जाता है। उदाहरणार्थ, दोनों महायुद्धों के बीच के काल में संयुक्तराज्य अमेरिका इसी मूल का शिकार था। इसी प्रकार एक राष्ट्र अपनी दृष्टि अति उच्च (too high) रखकर ऐसी नीतियों का अनुसरण कर सकता है जिन्हें उपलब्ध शक्ति के वन पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। यह गलती संयुक्तराज्य अमेरिका में सन् 1919 में शान्ति वार्ताओं के समय की थी। जैसा कि लॉयड जॉर्ज ने कहा था—‘ऐसा प्रतीत होता था कि अमेरिकियों ने ‘दसों निर्देशों’ (Ten Commandments) तथा ‘सरमन ऑन द माउण्ट’ (The Sermon on the

Mount) की पूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण कर रहा था। फिर भी जब व्यावहारिक प्रश्नों में सहायता और उत्तरदायित्व का ससय आया तो वे बिल्कुल पीछे हट गए। एक राष्ट्र बिना समुचित क्षमता के महान् भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा कर सकता है किन्तु इस प्रयास में वह सर्वनाश का भागी ही बनेगा। दोनों महायुद्धों के बीच पोलैण्ड के साथ असहयोग था। यह भी हो सकता है कि एक महाशक्ति होने के कारण कोई राष्ट्र उस घसीमित विजय-नीति के मार्ग पर अग्रसर हो जाए जो उसकी शक्ति के बाहर हो। ऐसा करने पर वह राष्ट्र 'असफल विश्व-विजेताओं' (The Unsuccessful World Conquerors) की श्रेणी में ही गिना जाएगा। सिकन्दर से हिटलर तक के इतिहास में ऐसे उदाहरण सरलता से ढूँढे जा सकते हैं।"

इस प्रकार विदेश-नीति की सीमाएँ उस उपलब्ध राष्ट्रीय शक्ति से निर्धारित होती हैं। इस नियम का केवल एक अपवाद हो सकता है कि जिस समय राष्ट्र का जीवन ही दाँव पर लगा हो उस समय राष्ट्रीय जीवन की नीति (The Policy of National Survival) राष्ट्रीय शक्ति के सभी विवेकपूर्ण विचारों पर हावी हो जाती है और संवत्काल शक्ति तथा नीति के बीच के सामान्य सम्बन्धों को पलट देता है तथा राष्ट्र अपने समस्त हितों को अपनी रक्षा के दाव पर लगा कर इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रयत्नों का आश्रय भी लेता है जो साधारण समय में विवेक के आधार पर उसके द्वारा सोचे भी नहीं जा सकते थे। उदाहरणार्थ, सन् 1940-41 के शीतकाल में ग्रेट-ब्रिटेन ने ऐसा ही किया था।

साधनों में सन्तुलन की समस्या

(The Problem of Balance Among Resources)

जब एक बार कोई सरकार राष्ट्र की विदेश-नीति और राष्ट्रीय शक्ति में सन्तुलन स्थापित कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में सन्तुलन स्थापित करना होता है। कोई भी राष्ट्र केवल इसलिए आवश्यक रूप से अधिकतम राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता कि वह प्राकृतिक साधनों में अत्यन्त सम्पन्न है अथवा उसके पास विशाल जनसंख्या है या उसने एक बहुत ही समृद्ध औद्योगिक और सैनिक संगठन का निर्माण कर रखा है। वह अधिकतम राष्ट्रीय शक्ति अभी प्राप्त कर पाता है जब उसके पास सही अनुपात में शक्ति के पर्याप्त साधन गुण और मात्रा दोनों में उपलब्ध हो। जिस समय ग्रेट ब्रिटेन अपनी शक्ति के शिखर पर था, उसके पास राष्ट्रीय शक्ति के अनेक तत्वों की कमी थी जैसे प्राकृतिक साधन, जनसंख्या की मात्रा और स्थल सेना। फिर भी उसने राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व नीतिना की इतना श्रेष्ठ बना लिया था कि उसने द्वारा वह समुद्री विजय की अपनी नीति पूर्ण सफलता के साथ संचालित कर सका जिसके कारण ब्रिटेन में विदेशों से उन कच्चे माल तथा खाद्य-पदार्थों का आना जारी रह सका जिनके बिना वह जीवित नहीं रह सकता था। इस नीति के तथा उपलब्ध प्राकृतिक साधनों और अपनी भौगोलिक स्थिति के सन्दर्भ में एक विशाल जनसंख्या तथा स्थायी सेना ग्रेट-ब्रिटेन के लिए लाभदायक

होने के स्थान पर असुविधाजनक ही होती। दूसरी ओर यदि वह मध्य युग की भाँति महाद्वीपीय विस्तार की नीति अपनाता तो उसको इन दोनों ही तत्त्वों की सदा आवश्यकता रहती।

एक विशाल जनसंख्या शक्ति का स्रोत होने के स्थान पर निर्बलता का कारण भी बन सकती है, जैसा कि भारत और कतिपय अन्य एशियायी राष्ट्रों के संदर्भ में कहा जा सकता है। यदि हम उपलब्ध साधनों द्वारा अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति नहीं कर पाते, यहाँ तक कि उसे आवश्यक भोजन भी नहीं दे पाते तो ऐसी जनसंख्या शक्ति की प्रतीक नहीं बन सकती। यदि निरंकुशतावादी तरीकों से विशाल औद्योगिक और सैनिक संगठनों वा जल्दी-जल्दी निर्माण भी कर लिया जाए तो राष्ट्रीय शक्ति के कुछ तत्त्व पैदा अवश्य हो सकते हैं, लेकिन साथ ही इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्त्व जैसे राष्ट्रीय मनोबल और जनसंख्या की शारीरिक समुत्थान शक्ति नष्ट भी हो जाते हैं। पूर्वी यूरोप के रूसी उपनिवेशों या पिछलग्गू राष्ट्रों के विकास की स्थितियों से यह बात स्पष्ट है। उपलब्ध औद्योगिक क्षमता से बढ़ कर विशाल सैनिक संगठनों के निर्माण का वास्तविक ध्रुव राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि नहीं है बल्कि राष्ट्र को निर्बल बनाना है। हंस मॉर्गेंथो का कहना है कि राष्ट्रीय संकटकाल के समय, जबकि राष्ट्र का जीवन ही दाव पर लगा हो, अमेरिकी सरकार को (इसी प्रकार किसी भी अन्य राष्ट्र की सरकार को) अपने लोगों को भस्म की जगह बन्दूकों दे देनी चाहिए; लेकिन यदि ऐसा संकट उपस्थित न हो तो सैनिक और नागरिक आवश्यकताओं के बीच नागरिक उपभोग के लिए पर्याप्त आर्थिक उत्पादन द्वारा सही संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। कोई भी सरकार राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करते समय अपने देश के राष्ट्रीय चरित्र के प्रश्न की ओर से उदासीन नहीं रह सकती। एक राष्ट्र उन्हीं कठिनाइयों के विरुद्ध ज़ान्ति कर सकता है जिन्हे दूसरा राष्ट्र सन्तोषपूर्वक भेलता चला जाता है और कभी एक राष्ट्र अपने हितों और अपने जीवन की रक्षा में स्वेच्छापूर्वक इतने महान् त्याग कर सकता है कि ससार चकित हो जाए।

जनता के समर्थन की समस्या

(The Problem of Popular Support)

मॉर्गेंथो का कथन है कि किसी भी आधुनिक सरकार ने, विशेषकर एक लोकतान्त्रिक सरकार ने, यदि उपर्युक्त दोनों संतुलनों में सफलता प्राप्त करती है तो भी उसने वास्तव में अपने दायित्व का केवल एक अंश ही पूर्ण किया है क्योंकि उसके समक्ष एक सबसे बड़ी कठिन समस्या और भी उपस्थित रहती है और वह है—जनता के समर्थन की समस्या। एक सरकार को अपनी विदेश-नीतियों के पक्ष में, और उन विदेश-नीतियों के समर्थन में राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों को जुटाने वाली गृह-नीतियों के पक्ष में अपनी जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन यह कार्य बहुत कठिन है क्योंकि जिन परिस्थितियों में विदेश-नीति के पक्ष में जन-समर्थन प्राप्त किया जा सकता है वे आवश्यक रूप से ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती जिनके अन्तर्गत एक विदेश-नीति को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

लोकतन्त्र की यह एक प्रवृत्ति है कि वह दूरदर्शिता की अपेक्षा क्षणिक भावेग की ओर जल्दी आकृष्ट होता है और एक परिपक्व परियोजना का तिरस्कार कर क्षणिक उन्माद के आनन्द को अधिक पसन्द करता है। फ्रांसीसी क्रान्ति के विस्फोट पर अमेरिकी लोकतन्त्र में जो प्रतिक्रिया हुई उससे इस प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। उस समय सामान्य बुद्धि वाले लोगों तक को स्पष्ट ग्रहसास था कि तत्कालीन प्रतिद्वन्द्विता में जो शीघ्र ही सम्पूर्ण यूरोप को खून की नदी में डुबो सकती थी, अमेरिकियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अमेरिकी जनता ने अपनी सहानुभूति को फ्रांसीसियों के पक्ष में इतनी उग्रता के साथ व्यक्त किया कि केवल जॉर्ज वाशिंगटन की कठोरता और अत्यधिक लोकप्रियता ही अमेरिकियों को इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने से रोक सकी। अपने नागरिकों के उदार, किन्तु अदूरदर्शी उन्मादों को सन्तुलित विवेक द्वारा दबाने के प्रयत्न में जॉर्ज वाशिंगटन को लोकप्रियता से ही हाथ धो बैठने की नीवत या गई और उस समय बहुमत ने उसकी नीति का तिरस्कार भी किया, लेकिन आगे चल कर सम्पूर्ण राष्ट्र ने वाशिंगटन की नीति का समर्थन किया। स्पष्ट है कि यदि वाशिंगटन-सरकार जनता के क्षणिक उन्माद से प्रभावित हो जाती तो जबरदस्त गलती कर बैठती, पर उसने विवेक से काम लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षणिक उन्माद जब शान्त हो गया तो वाशिंगटन की नीति को जनता का भरपूर समर्थन मिला।

मोंटेन्गो ने इस बात पर बल दिया है कि राजनीतिज्ञों और सरकार को अपने पक्ष में जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन विवेकशून्य होकर नहीं। हो सकता है कि क्षणिक भावेग में जनता जिस नीति का विरोध कर रही है, कुछ समय बाद वह उस नीति को पूर्ण समर्थन करे—क्योंकि वह नीति वस्तुतः राष्ट्रीय हित की सम्बद्धक है। एक सकल विदेश-नीति के संचालन के लिए जैसी विचारधारा की आवश्यकता होती है वह कभी-कभी उन विचारों के विपरीत हो सकती है जो आम जनता या उनके प्रतिनिधियों को प्रेरित करते हैं। राज्य के कर्णधारों के मस्तिष्क के विशेष गुण सदैव ही जनता की प्रतिक्रियाओं को अपने पक्ष में प्राप्त करने में सफल नहीं होते। राजनीतिज्ञों को शक्तियों के मध्य शक्ति के सन्दर्भ में राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। जनता का मस्तिष्क राजनीतिज्ञों की विचारधाराओं की सूक्ष्मताओं से अनभिज्ञ रहता है और फलस्वरूप वस्तु-स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। एक राजनीतिज्ञ को दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाकर चक्करदार मार्ग-चर्चने-चर्चने अपनी नीतियों की पूर्ति की ओर अग्रसर होना पड़ता है और कई बार समझौतावादी मार्ग अपनाकर अग्रसर भी बाट जोहनी पड़ती है। उसे समय के साथ चलना होता है और भावी बड़े लाभों के लिए वर्तमान में छोटे लाभ त्यागने पड़ते हैं। लेकिन सामान्य जनता की प्रवृत्ति यह होती है कि वह दुरस्त फल चाहती है और बल के वास्तविक लाभ को आज के दिखावे के लाभ पर बलिदान कर देती है। कोई भी अच्छा राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी अच्छी सरकार कल के वास्तविक लाभ को आज के साधारण बल्कि 'छलिया' लाभ पर बलिदान नहीं कर सकती।

जनमत कभी-कभी इतना उन्मादी यत्कि अन्धा हो जाता है कि एक अच्छी विदेश-नीति को बुरी विदेश-नीति और एक बुरी विदेश-नीति को अच्छी विदेश-नीति मान बैठता है, अतः विदेश-नीति का निर्धारण करते समय इन सम्बन्ध में किसी भी सरकार को दो अज्ञात गुप्त सक्तों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए—प्रथम, जिस नीति को सरकार वास्तव में अच्छा समझती है उसे जनमत की वेदी पर नहीं चढ़ा देने के मोह से बचना चाहिए, अन्यथा राष्ट्र के स्थायी हितों की यथैवेदी पर अस्थायी लाभों की ही प्राप्ति हो सकेगी, एवं द्वितीय, एक अच्छी विदेशी-नीति की आवश्यकताओं तथा जनमत के रुझानों के मध्य खाई को बढने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात् विवेकपूर्ण ढंग से सन्तुलनकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि जनमत के रुझानों से उचित समझीता करने के बजाय विदेश-नीति के सूक्ष्मतम व्यूह पर अडे रहने की नीति अपनाई गई तो इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता और इसी प्रकार यदि जनमत की मांग के औचित्य-अनौचित्य को एकदम अनदेखा करके विदेश-नीति का संचालन किया जाए तो इसमें भी खतरा है। वास्तव में एक अच्छे राजनीतिज्ञ और एक अच्छी सरकार से अपेक्षा की जाती है कि जब जनमत अविवेकपूर्ण ढंग से उन्मादी अवस्था में हो तो वह उसे किसी प्रकार शान्त कर दे और राष्ट्र के लिए हितकारी विदेश-नीति का अनुपालन करे, और यदि जनमत की मांग तर्कपूर्ण और उचित हो तो विदेश-नीति को रूपरेखा में सामयिक संशोधन करने को तत्पर रहे।

हंत मार्गेंग्वोका मत है कि अपनी विदेश और गृह दोनों ही नीतियों में किसी भी सरकार को तीन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए—

1. इस तत्त्व को मान्यता देनी चाहिए कि एक अच्छी विदेश-नीति की आवश्यकताओं और जनमत के रुझानों के मध्य का विरोध स्वाभाविक है और इसे कम किया जा सकता है, किन्तु उस खाई को गृह-विरोधी तत्त्वों को छूट देकर पाटा नहीं जा सकता।

2. शासन को यह समझना चाहिए कि वह जनमत का नेता है, न कि उसके दास। उसे यह समझना होगा कि जनमत कोई ऐसी स्थिर वस्तु नहीं जिसे जनमत-निग्रह-साधनों द्वारा उस ढंग से खोजा या वर्गीकृत किया जा सकता है जिस तरह कि एक धनस्पति-विज्ञानवेत्ता पेड़-पौधों को करता है। इसके विपरीत जनमत एक गतिमान और परिवर्तनशील तत्त्व है जो निरन्तर उत्पन्न होता चलता है और जिसे पुनः जन्म देने का दायित्व एक बुद्धिमान और कुशल नेतृत्व का है। यह किसी सरकार का ऐतिहासिक उद्देश्य है कि वह इस नेतृत्व के लिए आगे बढ़े, अन्यथा विरोधी नेता इस कार्य को हथिया लेंगे।

3. सरकार को अपनी विदेश-नीति के ऐच्छिक और अनिवार्य तथ्यों को पृथक् कर लेना चाहिए। ऐच्छिक तथ्यों पर तो उसे जनमत से समझौता करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, किन्तु अपनी अच्छी विदेश-नीति के समर्थन में उसे अपने स्वयं के भाग्य तक की दांव पर रख कर उसके लिए लड़ना चाहिए।

अन्त में, कोई भी सरकार जनमत की दीर्घ समय तक उपेक्षा नहीं कर सकती। एक सरकार को विदेश-नीति तथा उसके समर्थन में आवश्यक गृह राजनीति की सही परख हो सकती है, पर यदि वह इन नीतियों के पक्ष में जनमत प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो उसका श्रम बेकार हो जाएगा और राष्ट्रीय शक्ति के उन अन्य तत्वों को जिन पर कोई भी राष्ट्र गर्व कर सकता है, पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। आधुनिक लोकतान्त्रिक सरकारें इस सत्य की बारम्बार पुष्टि कर रही हैं।

गृह-शासन तथा विदेश-नीति

फिर भी किसी भी सरकार के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि वह अपनी विदेश-नीतियों के समर्थन में राष्ट्रीय जनमत का सहयोग प्राप्त कर ले। उसे अपनी गृह और विदेश-नीतियों के समर्थन में अन्य देशों के जनमत का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। यह आवश्यकता आधुनिक युग की विदेश-नीति के चारित्रिक परिवर्तनों की द्योतक है। आज विदेश-नीति परम्परागत कूटनीति और सैनिक शक्ति रूपी अस्त्रों द्वारा ही संचालित नहीं की जाती बल्कि उसका संचालन 'प्रचार' नामक एक नए और बिलक्षण अस्त्र द्वारा होना है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज तक शक्ति-सर्पण केवल सैनिक श्रेष्ठता और राजनीतिक प्रभुत्व तक ही सीमित नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ में मानव-मस्तिष्कों पर विजय का प्रश्न बन गया है। तो फिर किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसके कूटनीतिक कौशल और उसकी सैनिक क्षमता पर ही अवलम्बित नहीं है वरन् इस बात पर भी निर्भर है कि वह राष्ट्र दूसरे देशों को अपने राजनीतिक दर्शन, अपनी राजनीतिक सस्थाओं और राजनीतिक नीतियों के पक्ष में कहाँ तक आकर्षित कर पाता है। साधारण रूप से तो यह बात सभी राष्ट्रों पर लागू होती है, लेकिन विशेष तौर पर संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत संघ पर अधिक लागू होती है क्योंकि ये दोनों महाशक्तियाँ न केवल अति महान् राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में होड़ कर रही हैं बल्कि दो विभिन्न राजनीतिक दर्शनों, शासन-व्यवस्थाओं और जीवन-पद्धतियों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में भी परस्पर प्रतिद्वन्द्विता कर रही हैं। अतः जो कुछ भी ये महाशक्तियाँ करती हैं या नहीं करती हैं, जो कुछ भी वे प्राप्त करती हैं अथवा नहीं करती हैं, उनकी गृह और विदेश-नीतियों में इन बातों का इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप उनकी शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर पर यह बात ५.२१.१० पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए यदि एक राष्ट्र रंगभेद की नीति ५.१.१० है तो वह इस पृथ्वी के काले लोगों के मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करने के सर्प में असफल हो जाएगा। इसी तरह यदि एक कम विकसित राष्ट्र अपनी जनता के स्वास्थ्य, जीवन-स्तर आदि को आश्चर्यजनक रूप में बढ़ाने में सफल हो जाता है तो वह संसार के अविकसित क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से अपनी शक्ति की वृद्धि करने में सफल हो जाएगा। भारत गुट-निरपेक्ष नीति को कितनी सफलतापूर्वक अपनाता है, यह बात गुट-निरपेक्ष विश्व का नेतृत्व कर सवने की उसकी क्षमता के लिए निर्णायक सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व : विचारधारा, मनोबल एवं नेतृत्व, राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन

(Elements of National Power : Ideology,
Morale and Leadership, Evaluation
of National Power)

“एक राज्य की सेनाओं के आकार में वृद्धि घटती हो सकती है, उसका मनोबल गिर या उठ सकता है, नेतृत्व बदल सकता है, कच्चे माल का अभाव या बाहुल्य हो सकता है, प्राविधिक प्रक्रिया सुधर सकती है, युद्ध में प्रयुक्त होने वाले नए हथियारों का आविष्कार हो सकता है, महामारी, बाढ़ और भू-चाल उत्पादन गिरा सकते हैं, श्रमिकों की मार सकते हैं और मनोबल गिरा सकते हैं, सन्धियों की और तोड़ी जा सकती हैं—ये सब अवस्थाएँ राष्ट्रीय शक्ति के एक अथवा अनेक तत्वों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं और इस प्रकार किसी भी राष्ट्र की शक्ति-स्थिति में परिवर्तन का कारण बन सकती हैं।” —पामर एवं पर्किंस

विचारधारा (Ideology)

भूगोल, जनसंख्या, तकनीकी आदि जिन तत्वों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनकी प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि हम उनके अस्तित्व को देख सकते हैं और उनके प्रभाव को आँक सकते हैं, इसलिए आवश्यकतानुसार उनका नियमन एवं नियन्त्रण भी कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शक्ति के कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते और जिनके अस्तित्व का हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं। ये तत्व भौतिक न होकर मानवीय तत्व हैं जैसे, विचारधारा (Ideology), मनोबल (Morale) तथा नेतृत्व (Leadership)। इन मानवीय तत्वों का प्रभाव भौतिक तत्वों का प्रयोग करने में निर्णय-शक्ति का काम करता है। ये मानवीय तत्व भौतिक

रूप से व्यक्ति के दृष्टिकोणों, विश्वासों और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। राज्यों के व्यवहार पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक देश के लोग अपने भौतिक तथा राजनीतिक वातावरण के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे, इसका निर्धारण बहुत कुछ इन तत्वों के समुचित मूल्यांकन से किया जा सकता है। देश के विभिन्न सामाजिक समूह सामान्य दृष्टिकोणों, मूल्यों और लक्ष्यों में जितना अधिक भाग लेते हैं, वहाँ उतनी ही अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। प्रायः देखा गया है कि जिन देशों के दृष्टिकोणों और मूल्यों में समानता होती है, उनके पारस्परिक सम्बन्ध भी शान्तिपूर्ण, सहयोगपूर्ण और सुखीपूर्ण रहते हैं। जिस देश के लोगों के दृष्टिकोणों और मूल्यों के बीच एकसमता नहीं रहती, वहाँ प्रायः अस्थिरता और संघर्ष का बोलबाला रहता है। यही बात अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में दो अथवा अधिक देशों के पारस्परिक सम्बन्धों पर लागू होती है। राष्ट्रीय 'भक्ति' के मानवीय तत्त्व अर्थात् विचारधारा, मनोबल, नेतृत्व आदि देश के लोगों के दृष्टिकोणों, विश्वासों और मूल्यों से पर्याप्त प्रभावित होते हैं।

विचारधारा का अभिप्राय

'विचारधारा' शब्द लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराना है। वेब्सटर के नवीन अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोष के अनुसार 'विचारधारा' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 'डेस्टट डिट्रेसो' (1754-1836) द्वारा किया गया था जबकि कुछ लोगों का 'विचार' है कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सैम्युअल नेपोनियन ने किया। फामर एवं पेरिस का यह मत उपयुक्त प्रतीत होता है कि यद्यपि विचारधारा सम्बन्धी तत्त्व शताब्दियों तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के निरन्तर तत्त्व रहे हैं, लेकिन बीसवीं शताब्दी से पूर्व उनका कदाचित ही निर्णायक महत्त्व था। आधुनिक युग तो विचारधाराओं का ही युग है। विभिन्न विचारधाराएँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा विश्व-राजनीति में नई, जान फूँकने का काम कर रही हैं।

विचारधारा द्वारा एक देश की जनता अपने मूल्यों और दृष्टिकोणों को अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त करती है। पैडलफोर्ड एवं लिबन के अनुसार विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का निकाय है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। स्नाइडर एवं विल्सन ने लिखा है कि "एक विचारधारा जीवन, समाज और सरकार से सम्बन्धित विचारों का वह समूह है जो प्रायः सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक मामलों या युद्ध के नारों में उत्पन्न होती है और जिसका लगातार प्रयोग उसे एक विशेष समुदाय, जन या राष्ट्रीयता का प्रमुख विश्वास या मिथान बन देता है।" इसी तरह के मतानुसार विचारधारा व्यक्ति के प्रमुख विचारों की व्यवस्था है। ये विचार वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं, मूल्यात्मक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तथा उन प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने और

बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिसमें उनके विश्वास के अनुरूप तथ्यों को सर्वश्रेष्ठ रूप में साकार किया जा सकता है।¹ इस प्रकार सरकार, अर्थव्यवस्था, समाज या जीवन सम्बन्धी ग्रन्थों वाली के निश्चित विचार-समूह को हम विचारधारा कह सकते हैं। व्यापक अर्थ में विचारधारा के अन्तर्गत वे सभी वाद धारा जाते हैं जिन्हें हम सर्वाधिकारवाद, फासीवाद, नाजीवाद, प्रजातन्त्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, समष्टिवाद, भोधीवाद, माधोवाद या उदारवाद आदि नामों से सम्मोहित करते हैं। दुनिया के प्रमुख धर्मों-हिन्दू, इस्लाम, ईसाई—को भी हम विचारधारा मान सकते हैं। स्प्राउट ने विचारधाराओं को दो वर्गों में विभाजित किया है—राजनीतिक विचारधाराएँ और गैर-राजनीतिक विचारधाराएँ। स्प्राउट का मत है कि सांविधानिक जनतन्त्र, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद प्रमुख विचारधाराएँ हैं। हय जे. मॉन्टेग्यो ने अपने ग्रन्थ 'पॉलिटिक्स ऑफ नेशंस' में विचारधाराओं को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बाँटा है—

(1) -स्थापित (Status-quo) बनाए रखने वाली विचारधाराएँ, जैसे साम्राज्यवाद, शांति एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून।

(2) विस्तारवादी अथवा साम्राज्यवादी विचारधाराएँ, जैसे फासीवाद, नाजीवाद, माधोवाद आदि।

(3) अस्पष्ट तथा अनेकार्थी विचारधाराएँ जैसे आत्मनिर्णय का सिद्धान्त। अनेक विद्वानों ने विचारधारा का बहुत व्यापक अर्थ लगाया है और एक विचारधारा में अनेक विचारधाराओं को सम्मिलित किया है। उदाहरण के लिए, उदारवाद के अन्तर्गत जनतन्त्र के विभिन्न रूपों और व्यक्तिवादी विचारधाराओं को सम्मिलित किया जाता है तो सर्वाधिकारवाद के अन्तर्गत नाजीवाद, फासीवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराओं की गणना की जाती है। विचारधाराओं का वर्गीकरण विवादास्पद है, लेकिन इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति दो प्रमुख विचारधाराओं की रगस्थली है—जनतन्त्र और साम्यवाद। कुछ राष्ट्रों में दोनों की मुख्यवर्ती विचारधारा को 'जनतान्त्रिक समाजवाद' का नाम दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधाराओं के संघर्ष की बात आम हो गई है। राष्ट्रों के मध्य मतभेदों और संघर्षों का एक प्रमुख कारण उनकी परस्पर विरोधी विचारधाराएँ ही हैं।

विचारधारा का कार्य यह है कि यह विश्व की कुछ प्रमुख विचारधाराओं का विश्लेषण करते हुए विचारधारा के कार्य पर प्रकाश डालता है और अपने विश्लेषण में यह भी स्पष्ट किया है कि विचारधारा किस प्रकार दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य विवाद का मूलोपाय बन जाती है। एल्जर, हर्ज एवं केल्मेन का विश्लेषण इस प्रकार है—

1. 'Schleicher's Op. cit., पृष्ठ 43-47'।

2. एल्जर एवं केल्मेन : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पृष्ठ 43-47।

3. एल्जर एवं केल्मेन : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पृष्ठ 43-47।

“हाल की सभी विचारधाराओं में, विश्व के सभी मामलों पर बदाचित्त सबसे अधिक प्रभाव साम्यवाद का पड़ा है। साम्यवादी विचारधारा का आरम्भ कार्ल मार्क्स से हुआ। मार्क्सवाद के मौलिक स्वरूप में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सिद्धान्त नाम मात्र उल्लिखित था। मार्क्स के अनुसार, सभी प्रकार के वर्ग-समाज युद्धकारक है। युद्ध राष्ट्रों के बीच संघर्ष का नहीं, बल्कि उनके शासक वर्गों के पारस्परिक संघर्षों का द्योतक है, जिसमें शासित जनता का प्रयोग बलि के बकरे के समान किया जाता है। मार्क्सवादी संकल्पना के अनुसार मजदूर वर्ग के बीच एकता तथा उसके द्वारा विश्वव्यापी संघर्ष के द्वारा, जिस वर्गविहीन समाज की स्थापना की जाएगी, उसमें राष्ट्रों का स्थान समाजवादी भ्रातृभाव ले लेगा और इस प्रकार युद्ध सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।

मार्क्सवादी विचारधारा के सभी उत्तराधिकारियों ने, इस लक्ष्य को अपनी प्रत्याशा बनाया, पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के सम्बन्ध में इन सभी के बीच पर्याप्त मतभेद रहा। लोकतन्त्रीय समाजवाद ने तो नरमपथी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धान्तों को अपना लिया, पर साम्यवादियों ने तो लेनिन के साम्राज्यवादी सिद्धान्त के ही समान, इसे बुजुर्गों ‘भ्रम’ की सजा दी।

लेनिन का कहना था कि साम्राज्यवाद विश्व में, पूँजीवादी देशों और उनके हितों का प्रसार पूँजीवादी प्रणाली की परमावस्था है। जिन संघर्षों को, उनके कथनानुसार साम्राज्यवाद उत्पन्न करता है, उनके कारण—बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा निवेश के अवसर, कच्चे माल के स्रोतों पर अधिकार और सस्ते श्रम की उपलब्धि। इस प्रकार ये संघर्ष उस प्रणाली में ही सन्निहित हैं, जो देर-प्रवेर साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच विश्वव्यापी युद्ध उत्पन्न करती है। ये युद्ध की मजदूर वर्ग के सम्मुख वह भ्रम सुझावसर प्रस्तुत करेंगे कि उपनिवेशी तथा अर्द्ध-उपनिवेशी विश्व की शोषित जनता के सहयोग से वे विश्वक्रान्ति ला सकें और इस प्रकार पूँजीवाद को समाजवाद के रूप में बदल सकें।

लेनिन के सिद्धान्त ने, अवश्यम्भावी भविष्यवाणी के रूप में, विजेता बोल्शेविकवाद ही की विचारधारा का रूप ले लिया पर सोवियत शासकों के सम्मुख, शीघ्र ही एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। पहले उन्होंने जिस विश्वव्यापी क्रान्ति की आशा की थी, वह अब नहीं हुई, तब यह जटिल समस्या उठ खड़ी हुई है कि समाजवाद तथा साम्राज्यवाद की दो दुनियाओं के बीच किन प्रकार का सम्बन्ध स्थापित रहे। उन्हें इस सम्बन्ध में न तो पहले कभी कोई सन्देह था और न अब हो है कि साम्राज्यवाद और साम्यवाद के मध्य संघर्ष परस्पर विरोधी हैं, जो आगे चल कर विश्वव्यापी हो जाएँगे तथा अन्ततः समस्त विश्व में विजय साम्यवाद की की ही होगी, फिर भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दौड़-पेचों के बारे में साम्यवादी विचारधारा अनिश्चित तथा भ्रष्ट रही है।

लेनिन ने कहा था कि साम्यवादी देशों तथा उनकी चारों ओर से घेरने वाले साम्राज्यवादी देशों के बीच संघर्ष का होना अवश्यम्भावी है, किन्तु स्तालिन ने, अभी

तो 'शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व' का समर्थन किया और कभी-पूँजीपतियों पर आक्रमण किए जाने पर जोर दिया। अपने शासन के अन्तिम दिनों में, लेनिन के समान ही उसने भी साम्राज्यवादी शक्तियों के पारस्परिक युद्ध की अनिवार्यता पर जोर दिया, किन्तु इसके साथ ही साथ उसकी यह भी धारणा थी कि साम्यवादी देश अब पूर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और साम्राज्यवादी देशों के साथ उनकी लड़ाई को रोका भी जा सकता है। स्टालिन के बाद ख्रुश्चेव ने यह दावा किया कि सोवियत संघ के अणु शक्ति सम्पन्न हो जाने के फलस्वरूप साम्यवादी देशों पर, साम्राज्यवादियों के आक्रमण का खतरा टल ही नहीं गया है, बल्कि अब साम्राज्यवादियों की आपसी लड़ाइयों को भी रोका जा सकता है। इस प्रकार, उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि लेनिन का 'युद्ध की अनिवार्यता' का सिद्धान्त अब पुराना पड़ गया है। इस सम्बन्ध में 'साम्यवादी' अनिवार्यता की गुँजाइश नहीं रही है तथा वर्तमान में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और अन्त में हिंसा के बिना ही पूँजीवाद को समाजवाद के रूप में बदल देना, केवल सम्भव ही नहीं, बल्कि श्रेयस्कर भी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर होने वाले युद्ध का अर्थ तो सबका विनाश या कहिए सर्वनाश ही है। फिर भी उनकी यह गान्धिता बनी रही कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आर्थिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धियों के रूप में वर्ग-संघर्ष चलता ही रहेगा।

इसके विपरीत, साम्यवादी चीन के नेता, युद्ध की अनिवार्यता के सिद्धान्त में पूर्णतया आस्था नहीं रखते हुए भी यह कहते हैं कि दृढ़ और शक्तिशाली नीति का अनुसरण करके ही साम्राज्यवादी आक्रमण को रोका जा सकता है। उनकी यह मान्यता रही है कि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देने वाली कम खतरे की नीति तो ऐसे खतरे को और भी अधिक बढ़ाती है। देशगत अन्तिम के सम्बन्ध में, विशेषतः अल्पविकसित देशों के सन्दर्भ में, माओत्से-तुंग के विचार इस बात पर जोर देते हैं कि विश्व में हिंसा जरूरी है और साम्यवादी खेमों का यह कर्तव्य है कि वह यत्र-तत्र-सर्वत्र मुक्ति-युद्धों का समर्थन कर, समस्त विश्व की आन्तिकारी शक्तियों की सहायता करे। इस सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि सोवियत संघ की रीति-नीति शान्तिपूर्ण परिवर्तन पर जोर देती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सोवियत संघ तथा चीन के मध्य विद्यमान विचारधारा विवादों के प्राधारभूत मतभेदों को, यदि हम एक ओर रख दें तो देखेंगे कि इन देशों के नेताओं के बीच मुख्य मतभेद युद्ध-कौशल तथा रणनीति से ही सम्बन्धित है। ये मतभेद विशेषतया इस सम्बन्ध में हैं कि अपने सिद्धान्त उद्घोषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किस सीमा तक टकराव आवश्यक है। दोनों ही पक्ष इस बात से सहमत हैं कि साम्यवादी खेमों के बीच सैद्धान्तिक समानता और वैचारिक एकता का होना आवश्यक है। जैसा कि इस विचारधारा के इतिहास में पहले भी प्रायः घटित हो चुका है, दोनों विवादी पक्षों के बीच फूट का मुख्य कारण यह रहा है कि इनमें आपस में इस प्रश्न पर मतभेद नहीं है कि सैद्धान्तिक विवाद का या वैमत्य की स्थिति में निर्णय का अधिकार किसे प्राप्त हो। सोवियत संघ का यह

दया कि सैद्धान्तिक प्रधानता का अधिकार उसे ही प्राप्त हो, चीन को मान्य नहीं है और वस्तुतः यही बात दोनों के मध्य विवाद का मूलाधार है।

ऊपर जिन बातों पर विचार हुआ है, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वदेशिक मामलों में विचारधारा का क्या स्थान होता है, विशेषतया हाल ही में, ऐसे प्रश्न कम देखने में आए हैं, जिनका सैद्धान्तिक ढाँचे से सम्बन्ध न हो, इसलिए प्रायः प्रेक्षक, व्यवहारज्ञ तथा सिद्धान्तकार, कारण और प्रभाव की समस्या की ओर अपना ध्यान अधिक देने लगे हैं। प्रश्न यह है कि सैद्धान्तिक विचारधाराएँ, घटनाओं तथा नीतियों के प्रमुख कारण हैं क्या वे गौण घटनाएँ हैं, जिनका कार्य राष्ट्र और शक्ति-गुटों के सामरिक, आर्थिक व अन्य हितों की व्याख्या या रक्षा करना या उनके मूल कारणों पर पर्दा डालना मात्र है? उदाहरणार्थ, इतिहास की सर्वाधिक शक्तिशाली विचारधाराओं में से एक मार्क्सवादी विचारधारा की व्याख्या के अनुसार पूँजीवादी विचारधारा वस्तुतः आर्थिक हितों का तथा वर्ग हितों का ऊपरी ढाँचा मात्र है।

किस विचारधारा में, किस वर्ग के कौन से हित निहित होते हैं, इनका पता करना कठिन कार्य नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषयक प्रचलित अभी हाल के सिद्धान्तों में शक्ति-हितों और राष्ट्रीय हितों पर जोर देने की जो मयार्थवादी प्रवृत्ति आई है उसका भी कारण स्पष्ट है। सत्ता हविष्याने के महत्वाकांक्षी वे सभी आन्दोलन, जिनमें हिंसे से अधिक प्रभाव प्रायः विचारधारा का होता है, वस्तुतः उन शक्ति गुटों से प्रेरित होते हैं, जिनके मुख्य प्रेरक तत्त्व उनके अपने हित ही होते हैं। निःसन्देह इस प्रकार के विश्लेषण के लिए गहन अध्ययन और पैनी दृष्टि की आवश्यकता है।

यह दृष्टव्य है कि विचारधाराओं पर आधारित नीतियों का प्रयोग असैद्धान्तिक तौर पर शायद नहीं किया जाता हो। इनका प्रयोग यदि विचारधाराओं में नहीं तो विचारों के पर्यावरण में इस प्रकार किया जाता है कि नेताओं तथा जनता या दोनों में से किसी एक के दृष्टिकोण पर इनका प्रभाव पड़े। इस सम्बन्ध में प्रायः कोई समान अनुभूति नहीं होनी। अत्यन्त मयार्थवादी राज-नेता भी सत्ता को, यदि पर्दे से नहीं तो 'प्रिज्म' से देखते हैं और विदेशी मामलों में सामान्यतया अपने व्यापारिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं। कोई भी साम्यवादी नेता, विश्व के मामलों के प्रति बिना ही मयार्थवादी तथा निर्मम क्यों न हो, पर जब वह संसार की वर्ग-संघर्ष की दृष्टि से देखता है तो उसकी यही धारणा होनी है कि सारा संसार, शान्तिप्रिय शक्तियाँ और आक्रामक शक्तियों के मध्य बँटा हुआ है। यदि हम यह भी स्वीकार कर लें कि स्तालिन, किसी हद तक सैद्धान्तिक तथ्यों से, स्वयं को विलुप्त हो अलग कर चुका था और संसार को केवल शक्ति ही की दृष्टि से देखने लगा था, तो भी यह मानना पड़ेगा कि वह अपने घर, अपने देश की जनता तथा अन्य देशों के साम्यवादियों के साथ साम्यवादी विचारधारा तथा सिद्धान्तों के माध्यम से ही सम्पर्क बनाए रख सकता था। इसी प्रकार, आज भी रूस और चीन के बीच सम्बन्धों को बिगाड़ने की

मुख्य जिम्मेदारी विचारधारा पर ही आसपास होनी है। इन दोनों देशों के मध्य, पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में किनना भी विरोध क्यों न रहा हो, पर विचारधारा सम्बन्धी मतभेद यदि नहीं हुए होते तो उनका वैमत्यपूर्ण संघर्ष निश्चय ही इतना उग्र रूप धारण नहीं कर पाता कि समस्त विश्व के साम्यवादी देश तथा दल उससे प्रभावित हो वैमत्य की दल-दल में घँस जाते।

विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति के सन्दर्भ रूप में

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को वास्तविक तत्त्व तब माना जाता है जब उसे राष्ट्रीय शक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है। जब शक्ति विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय आकांक्षा का साधन बन जाती है तो विचारधारा प्रबल हो उठती है। शक्ति के अभाव में विचारधारा निष्क्रिय है, महत्वहीन है और उम्मे हम केवल मिले-जुले खोखले विचारों की धारा मात्र कह सकते हैं। विश्व में साम्यवादी विचारधारा का भय मार्क्स या लेनिन के विचारों से पैदा नहीं हुआ बल्कि रूस और चीन की शक्ति ने जो, साम्यवाद के रक्षण, प्रसार और प्रभुत्व के लिए कृतसंकल्प है, उसे एक प्रमुख विचारधारा बना दिया।

विस्थापित दार्शनिक बट्टेण्ड रसेल ने विचारधारा को राज्य-शक्ति का एक आवश्यक तत्त्व माना है। यह राष्ट्रीय शक्ति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है—

1. विचारधारा राष्ट्रों के नियामकों के लिए एक सामान्य स्तर निर्धारित करती है जिसके अधीन व्यक्तियों और वर्गों को एक साथ एकत्रित किया जा सकता है। विचारधारा में वह शक्ति है जो एक उत्तेजित और असंगठित गतिविधि को एक संगठित और संगठित राजनीतिक आन्दोलन में बदल देती है। विचारधारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का एक निकाय होती है जो समाज या राष्ट्र के लक्ष्यों को स्पष्ट करती है जिससे जनता का मनोबल ऊँचा उठता है, जनता में लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल प्रेरणा जाग्रत होती है और जनता अनुशासन एवं आज्ञापालन की अभ्यस्त हो जाती है। इतिहास बताता है कि जब कभी किसी विचारधारा को जनता ने दृढ़ता से अपना लिया तभी उस विचारधारा ने जनता के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को भारी शक्ति प्रदान की, देश में वह फिजा फैला कर दी जिसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए, अपने राजनीतिक प्रभुत्व की भूख को मिटाने के लिए राष्ट्रीय शक्ति के प्रसार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उदाहरण के लिए, नाजीवादी विचारधारा ने जर्मन जनता को जिस रूप में संगठित, आक्रामक और विस्तारवादी बना दिया था वैसे उदाहरण इतिहास में कम ही देखने को मिलते हैं।

2. जिस राष्ट्र की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती अथवा जो राष्ट्र अनेक विचारधाराओं का शिकार होता है, वह सरलता से विदेशी प्रचार-प्रभाव में आ

जाता है। ऐसा राष्ट्र अपनी शक्ति का सगुचित विकास नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, द्वितीय महायुद्ध काल में फ्रांस में कोई निश्चित विचारधारा-जनित शक्ति प्रभावी नहीं थी, हिटलर ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और वहाँ पंचगमियों (Fifth Columnists) को संगठित कर फ्रांस को आन्तरिक रूप से और भी दुर्बल बना दिया तथा युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद के युग में देखा गया है कि जिन अफ़ेशियाई राष्ट्रों में अनेक विचारधाराएँ प्रचलित थी वहाँ इस फूट और दुर्बलता का साम्यवादियों ने लाभ उठाने की पूरी और बहुत हद तक सफल चेष्टा की। चीन का गृहयुद्ध परस्पर विचारधाराओं का युद्ध था जिसमें साम्यवादियों ने विजय प्राप्त की जिसके फलस्वरूप 'लाल चीन' का उदय हुआ। विश्व नेतृत्व की आकांक्षी साम्यवादी शक्तियों ने विभिन्न देशों में साम्यवादी दलों के संगठन में सहयोग देने की नीति इसी आधार पर अपनाई है कि उन देशों में व्याप्त विरोधी विचारधाराओं की फूट को अधिकाधिक चौड़ा किया जाए और साम्यवाद समर्थक तत्वों को साल भण्डे के नीचे एकत्र कर साम्यवाद की विजय का प्रयत्न किया जाए।

जिस विचारधारा को एक देश मानता है उसी विचारधारा को मानने वाले दूसरे देशों की सद्भावना और मैत्री उसके प्रति रहना स्वाभाविक है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में दो अथवा अधिक राष्ट्रों की मैत्री का मार्ग तब अधिक प्रशस्त हो जाता है जब उनके राजनीतिक सिद्धान्त, उनकी आर्थिक नीतियाँ, उनकी विदेश-नीतियाँ मिलती-जुलती हों या कम से कम एक दूसरे की विरोधी न हों। अमेरिका और पश्चिमी जगत् के बहुत से यूरोपीय राष्ट्र लोकतन्त्र के समान आदर्शों से प्रेरित और प्रभावित होकर ही साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध मोर्चा सम्भाले हुए हैं। 'लोकतन्त्र विश्व' और 'साम्यवादी विश्व' के बीच विरोध अथवा सघर्ष की स्थिति इसीलिए है कि दोनों पक्षों के राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक आदर्श भिन्न-भिन्न हैं और एक के अहित में दूसरा अपना हित समझता है।

3. कुछ राष्ट्रों की जनता यद्यपि विचारधारा की दृष्टि से विभाजित होती है, लेकिन उसके राजनीतिक लक्ष्य लगभग समान होते हैं। आधुनिक इंग्लैण्ड की जनता रूढ़िवादी, उदारवादी और समाजवादी वर्गों में बँटी है, लेकिन राजनीतिक लक्ष्यों में बहुत-कुछ एकरूपता है, विदेश-नीति के क्षेत्र में बहुत-कुछ समान लक्ष्य हैं। भारतीय जनता भी विभिन्न विचारधाराओं में विभाजित है और फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन या जापान की जनता की भी कोई एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है पर विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद भारत की जनता में मौनिक एकरता विद्यमान है। भारतीय एकरता के बारे में 'विभिन्नताओं में एकरता' की कहावत प्रसिद्ध है। यही बात बहुत से अन्य देशों पर न्यूनाधिक रूप में लागू होती है। इन देशों की जनता वास्तव में अपने आन्तरिक मतभेदों को लोकतान्त्रिक तरीकों से दूर करने की अभ्यस्त हो गई है। संकटकाल में अथवा किसी भी विदेशी आक्रमण के समय सारा राष्ट्र अपने मनभेदों को भुना कर एकजुट हो जाता है, सभी विचारों के लोग

राष्ट्रीय सेवा और त्याग के लिए तैयार हो जाते हैं। सन् 1962, 1965 और फिर 1971 में यही कहानी भारत की जनता ने दोहराई और इस प्रकार अपनी राष्ट्रीय शक्ति का परिचय दिया। तथापि उल्लेखनीय बात यह है कि राष्ट्रीय भावनाओं के साथ मेल न खाने से इन देशों में साम्यवादी दल की स्थिति और नीति-नीति अलग-थलग रही है। हर देश में साम्यवादी दल का सामान्य रवैया प्रायः यही देखने में आया है कि वह स्वयं को राष्ट्र विशेष का दल न समझ कर विराल साम्यवादी आन्दोलन का अंग मानते हुए अपने सिद्धान्तों और विचारों को दूसरों पर थोपना चाहता है, देश की विद्यमान सस्याओं को मिटा कर अपनी सस्याएँ लादना चाहता है। यही कारण है कि लोकतान्त्रिक देशों में सरकारें साम्यवादी विचारधारा के प्रति प्रायः कठोरता का रुख अपनाती हैं। लेकिन साथ ही वह बात भी है कि वही साम्यवादी दल, जो पहले राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लीन रहता है, सत्तारूढ़ होने पर कट्टर राष्ट्रवादी बन जाता है। आशय यह है कि विचारधारा सत्ता के साथ जुड़ कर हर दृष्टि से राष्ट्रीय शक्ति के प्रदर्शन और प्रभा को प्रोत्साहन देती है।

4. विचारधारा का प्रयोग प्रायः सभी राष्ट्र अपने हितों के संरक्षण-सम्बर्धन में किया करते हैं। प्रायः हर राज्य अपनी विचारधारा के आधार पर अपने कामों को 'शक्ति के लिए संघर्ष' में उचित ठहराता है। वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक आड़ में प्रत्येक देश अपनी व्यावहारिक नीतियों और आचरण पर पर्दा डालता है। यूरोपीय साम्राज्यवाद के उत्कर्षकाल में पश्चिमी राष्ट्र 'गोरे व्यक्ति के बोझ' (White Man's Burden) के आधार पर अपने विस्तारवाद को उचित ठहराते थे। अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को इस विचारधारा के आधार पर उचित ठहराया जाता था कि 'गोरी जाति का कर्तव्य विश्व को सम्य बनाना है। विचारधारा के आधार पर ही 19वीं शताब्दी में अमेरिकी रिपब्लिकन सिद्धान्तों के विश्व में प्रचार-प्रसार और अमेरिका के लिए प्रादेशिक क्षेत्रों की प्राप्ति को अपना कर्तव्य मानते थे। साम्यवादी शक्तियाँ अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति को 'साम्यवादी विचारधारा' के आवरण में ही छिपती हैं। पैडलफोर्ड एवं लिंकन का कथन है—“रूस के बाहर साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार करके, स्थानीय दलों को संगठित करके, तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वालों को प्रशिक्षण देकर और दूसरे देशों में उन्हें भेज कर तथा स्थानीय संकटों से लाभ उठाकर ही कमलिन अपनी शक्ति को चेकोस्लोवाकिया से चीन तक विस्तृत करने और यूरोप तथा एशिया के अन्य स्थानों में अपना प्रभाव फैलाने में सफल हुआ है। नही-नही साल सेना का सहयोग लेना पड़ा है, लेकिन हर जगह नहीं।”¹ वास्तव में महायुद्धोत्तर युग में रूसी 'विजय' सैनिक शक्ति की अपेक्षा 'विचारधारा की शक्ति' की अधिक रही है।

5. विचारधारा विभिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बाँधती है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व के दशक में चीन-जापान संघर्ष में संयुक्तराज्य अमेरिका सहानुभूति चीन के साथ बहुत कुछ इसीलिए थी कि ईसाई धर्म-प्रचारकों को चीन में कार्य करने की छूट थी और अमेरिका एवं उसके साथी राष्ट्रों को भरोसा था कि चीन धीरे-धीरे ईसाई धर्म तथा जनतन्त्र की ओर बढ़ रहा है। समान धर्म और विचारधारा के प्रभाव का दूसरा ज्वलन्त उदाहरण 'अरब राज्यों का संघ' है जिसके सदस्य इस्लाम के अनुयायी और यहूदियों के विरोधी हैं, अतः वे विषय आन्तरिक मतभेदों के बावजूद इजरायल के विरुद्ध भावनात्मक रूप से संगठित हो जाते हैं। यहूदी विरोध विचारधारा उन्हें राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में अनेक अवसरों पर एकजुट कर देती है। पेंडलफोर्ड एवं लिंकन ने लिखा है कि 19वीं सदी के अन्तिम चरण और 20वीं सदी के प्रारम्भिक चरण में यूरोपीय समाजवादी नेताओं ने समाजवाद के सिद्धान्तों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न किया लेकिन समाजवादी देशों के बीच एकता न होने तथा राष्ट्रीय भावनाओं के अपेक्षाकृत अधिक प्रबल होने के कारण उनके ये प्रयत्न अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके। पर यदि पश्चिमी यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में कोई ऐसा संगठन स्थापित किया जाए तो वह सम्भवतः सफल हो सकता है। राजनीतिक संगठन पर विचारधारा के प्रभाव का एक अन्य उदाहरण यह लिया जा सकता है कि अटलाण्टिक चार्टर में निहित सिद्धान्तों तथा अमेरिकी राष्ट्रपति स्व. रूजवेल्ट द्वारा उद्घोषित मूलभूत स्वतन्त्रताओं के आधार पर ही सैद्धान्तिक आधारभूमि तैयार हो सकी जिसके अन्तर्गत द्वितीय महायुद्ध-काल में मित्रराष्ट्र घुरीराष्ट्रों के विरुद्ध संगठित हुए। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व के रूप में विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है जो अनेक अवसरों पर राष्ट्रों के मध्य एकता स्थापित करने में सहायक होती है।

विचारधारा का आश्रय क्यों लिया जाता है ?

उपयुक्त विवरण यह प्रस्थापित करता है कि विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का प्रबल और आज के युग में अत्यन्त शक्तिशाली तत्त्व है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धान्त के प्रणेता 'शक्ति-संघर्ष' को महत्त्वपूर्ण मानते हैं और उनका कहना है कि विचारधारा अथवा सिद्धान्त इस शक्ति-संघर्ष की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। विश्व-राजनीति में जो वास्तविकता है और जो दिखाई देती है उन दोनों के बीच पर्याप्त अन्तर है। राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियाँ निर्धारित करते हैं, किन्तु ये नीतियाँ उनके द्वारा नैतिक, वानुनी या जीव-शास्त्रीय अर्थ में अभिव्यक्त की जाती हैं। बहने का अर्थ यह है कि नीति के सही रूप को सैद्धान्तिक न्यायोचितता एवं बौद्धिकता के द्वारा छिपाया जाता है। मॉर्गेन्थो के मतानुसार जो लोग शक्ति-संघर्ष में जितने उलझे रहते हैं वे इस बात को उतना ही कम देख पाते हैं कि यह शक्ति-संघर्ष विसर्जित हो रहा है। राजनीतिक रंगमंच के अभिनेता राजनीतिक विचारधारा के पीछे की राजनीतिक क्रियाओं की गहरी प्रकृति को दिखाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति संघर्ष से जितना अधिक दूर होता है वह उम्मी

सही प्रकृति को समझने में उतना ही अधिक समय होता है। इस आधार पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि एक देश विशेष की राजनीति को उसके मूल निवासियों की अपेक्षा प्रायः विदेशी अधिक अच्छी तरह समझ पाता है। साथ ही एक विद्वान् अध्ययनकर्ता राजनीतिज्ञों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त कर लेता है। राजनीतिज्ञों की यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे जो कुछ भी करते हैं उसे छिपाना चाहते हैं और इसलिए अपने कार्यों को शक्ति की शब्दावली में व्यक्त करके नैतिक और कानूनी सिद्धान्तों या जैविक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में प्रकट करते हैं। मॉर्गेंथो के शब्दों में जबकि समस्त राजनीति आवश्यक रूप से शक्ति की खोज है, विचारधारार्थ इस शक्ति-संघर्ष को ऐसा रूप देती हैं जो नेताओं और उनके श्रोताओं के लिए मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक रूप से स्वीकार्य हो।

कहा जाता है कि राजनीति की यह प्रकृति है कि वह राजनीतिक रंगमंच के अभिनेता को अपने कार्यों के तत्कालीन लक्ष्य को छिपाने के लिए विचारधारा का प्रयोग करने के लिए बाध्य करती है। प्रत्येक राजनीतिक कार्य का तात्कालिक उद्देश्य शक्ति है और राजनीतिक-शक्ति व्यक्तियों के कार्यों एवं मस्तिष्क की शक्ति होती है। शक्ति की राजनीति में जो व्यक्ति दूसरों की शक्ति का विषय है वह दूसरों पर अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता और है दूसरे उस पर अपनी शक्ति स्थापित करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वभाववश अपनी शक्ति-प्राप्ति की इच्छा को कानूनी और न्यायशील मानता है तथा दूसरों की ऐसी इच्छाओं को जो उसे अपनी शक्ति से प्रभावित करने का प्रयास करती हैं वह अनुचित और अन्यायपूर्ण मानता है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से सोवियत संघ अपनी नीति को सुरक्षा की दृष्टि से न्यायोचित मानता है, किन्तु अमेरिकी शक्ति के प्रसार को वह विश्व-विजय की तैयारी या साम्राज्यवादी प्रयास कह कर उसकी खालीचता करता है। दूसरी ओर संयुक्तराज्य अमेरिका भी रूस की महत्त्वाकांक्षाओं को यही उपाधि प्रदान करता है और अपने अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता बताता है। मॉर्गेंथो द्वारा उद्धृत जॉन एडम्स के ये शब्द उल्लेखनीय हैं कि शक्ति हमेशा यह सोचती है कि इसकी आत्मा महान् है, इसके दृष्टिकोण व्यापक हैं तथा जिस समय ईश्वरीय कानूनों को तोड़ रही है उस समय यह ईश्वर की सेवा कर रही है।¹

यदि कोई देश खुले रूप में स्वीकार करले कि वह शक्ति का आकांक्षी है और इसीलिए दूसरे राष्ट्रों की महत्त्वाकांक्षाओं का विरोध कर रहा है तो वह राष्ट्र न केवल कठिन स्थिति में पड़ जाएगा बल्कि उसे शक्ति-संघर्ष में भी नुकसान पहुँचेगा। इस प्रकार की स्पष्टवादिता एक ओर तो दूसरे राष्ट्रों को उसके विरुद्ध बना देगी जो संयुक्त होकर उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करेंगे अथवा उसकी विदेश-नीति के लक्ष्यों को पूरा नहीं होने देंगे तथा दूसरी ओर वह राष्ट्र सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्डों को ठुकरा देने के कारण ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहाँ स्वयं की

विदेश-नीति को वह आधे मन से अथवा बुरे भाव से सम्पन्न करेगा। यह कहा जाता है कि अगर कोई सरकार जनता को अपनी विदेश-नीति के समर्थन में लाना चाहती है या समस्त राष्ट्रीय शक्तियों तथा साधनों को उसके पीछे लगा देना चाहती है तो उसे चाहिए कि जीव-शास्त्रीय आवश्यकताओं पर जोर डाले, जैसे राष्ट्र का अस्तित्व, आदि। नैतिक मिद्धान्तों जैसे न्याय पर जोर डालना भी उपयोगी हो सकता है, किन्तु उसे शक्ति की शब्दावली में नहीं बोलना चाहिए। केवल इसी मार्ग को अपनाकर एक राष्ट्र बलिदान के लिए उत्साह एवं स्वेच्छा प्राप्त कर सकता है जिसके बिना उसकी विदेश-नीति शक्ति के अन्तिम मापदण्ड से बाहर नहीं निकल सकती।

विचारधारा का राष्ट्रीय शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव

विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति पर सदैव सकारात्मक प्रभाव ही डाले, यह आवश्यक नहीं है। अनेक दृष्टियों में और अनेक अवसरों पर विचारधारा का राष्ट्रीय शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, जहाँ-जहाँ नाजीवाद ने जर्मन जनता का अन्ध-समर्थन प्राप्त किया और जर्मनी की राष्ट्रीय शक्ति को प्रबल बनाया वहाँ उसने हमारे राष्ट्रों के कोप और विरोध को आमन्त्रित कर जर्मनी को विनाश के बगार पर भी ला पटवा। विचारधारा यदि राज्यों की एकता और मंगल में सहायक होनी है तो दूसरी ओर वह कई बार उनके सघर्ष और विघटन का कारण भी बन जाती है। पामर और पकिंस के शब्दों में, "विचारधाराएँ, वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष का शक्तिशाली साधन होती हैं और वे सभी सघर्षों के शान्तिपूर्ण समाधान के कार्यों को बहुत अधिक जटिल बना देती हैं।"¹ इसका एक मुख्य कारण यह है कि विचारधारा कई बार सामान्य विवेक का उल्लंघन कर भावनाओं के तीव्र आवेग द्वारा निर्देशित होती है और वैसे भी सामान्यतः इसके मूल में विवेक की अपेक्षा भावनात्मक वेग ही अधिक प्रबल होता है। यदि विचारधारा का प्रयोग बड़ी कट्टरता से किया जाए तो राष्ट्रीय शक्ति पर इसका अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसके अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं, यथा—

1 विरोधियों के बीच समझौते और विचार-विमर्श के मार्ग कष्टवाचीएँ हो जाएँगे, यही तब कि समझौता असम्भव भी बन सकता है।

2 समझौते के क्षेत्र ढूँढ़ने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को घटका लगेगा और निराशा मिलेगी।

3 राष्ट्र में इनकी उत्तेजना और विम्वारवादी आकांक्षा व्याप्त हो जाएगी कि राष्ट्रीय शक्ति के आत्मघाती विस्फोट को रोचना असम्भव प्रायः हो जाएगा। जर्मनी में हिटलर और उनकी नाजी विचारधारा विस्फोट के लिए उत्तरदायी थी।

4 राष्ट्रीय सम्मान का अनुचित रूप में त्याग अथवा बलिदान किए बिना अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करना बंठित हो जाएगा।

5. शस्त्रीकरण और सैनिकवादी आर्वाभासों को प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान इस्लामी विचारधारा को इतनी कट्टरता और मदान्धता से अपनाए हुए है कि वह भारत से 'हजारों वर्ष' लड़ते रहने की वान धाज भी नहीं भूला है जबकि सन् 1965 और 1971 में उसे शिक्षा मिल चुकी है और विखण्डित भी हो चुका है। आधुनिक राष्ट्रों में मजहब की कट्टरता का ऐसा उदाहरण बिले ही देखने को मिलता है।

6. कूटनीतिक समझौतों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का उपयोग किया जाना कठिन हो जाएगा। राष्ट्रों का प्रयास यही होगा कि वे सम्मेलनों का उपयोग अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए करें।

पामर एव पकिंस का विचार है कि यदि उन दो देशों के बीच जो अपनी-अपनी विचारधारा का कट्टरता से पालन व प्रचार करने हैं, मन-मुटाव एव वैमनस्य पैदा हो गया तो वह एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय सकट बन कर रहेगा जिससे पार पाना असम्भव हो जाएगा। विचारधारा सम्बन्धी सदैव आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और शीत-युद्ध का केन्द्र-बिन्दु रहा है। पर, विचारधारा के दन नकारात्मक प्रभावों के बावजूद समझौतावादी तत्वों का अपना महत्व होना है, इसमें सन्देह नहीं यदि राष्ट्रों में समझौतावादी प्रवृत्ति का बिलकुल ही लोप हो गया होना तो हम शान्ति और सहस्रान्तत्व की वान न करते तथा पुनर्निर्माण, आर्थिक सहायता, तकनीकी प्रसार आदि क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वान न सोचते। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति-संपर्ष का खेल निरन्तर होना रहता है, लेकिन साथ ही सहयोग और सामञ्जस्य की शक्तियाँ राष्ट्रों को हिंसात्मक सधर्षों अथवा युद्धों में उलझने से बचाती भी रहती हैं और युद्धों को शान्त करती हैं। राजनीतिक समझौतों द्वारा किसी राष्ट्र की विचारधारा को नहीं बदला जा सकता, किन्तु सहयोग के आधार तो पैदा किए ही जा सकते हैं।

विचारधारा और विदेश-नीति

विचारधारा और विदेश-नीति के पारस्परिक सम्बन्ध एव अन्तर को समझना भी आवश्यक है। इसका अग्रध्या स्पष्टीकरण डॉ. गोविन्द पुरपोत्तम देवगण्ड ने अपने एक लेख में किया है। उन्ही के शब्दों में—

“हम विदेश-नीति और विचारधारा के परस्पर सम्बन्ध पर विचार करेंगे। यह कुछ कठिन विषय इसलिए है कि प्रत्येक आदमी, जो एक क्षण विदेश-नीति और विचार को परस्परवलम्बित मानता है, तो दूसरे ही क्षण अपने कथन से मुकर जाता है, इससे इकार कर देता है। यह अग्रनिमित्त दृष्टान्त से स्पष्ट हो जाएगा। विदेश-नीति मुख्यतया राष्ट्रीय हित से सम्बद्ध होती है। ऐसा मानने वाले किसी समीक्षक को नीतिज्ञ। उताका यह प्रिय आग्रह ठीक है किन्तु वह विदेश-नीति की विचारधारा के सन्दर्भ में ठीका करने से कतराता नहीं। 1971 में श्री लंका में जनता विमुक्ति परेरुणा नामक संपठन जब आन्दोलन के रास्ते पर था तब भारतीय सरकार ने

श्रीमती भण्डारनायक की सरकार के प्रति सहानुभूति दिखायी थी। मेरे एक मित्र को, जो विदेश-नीति और राष्ट्र-हित के परस्पर सम्बन्धों को स्वीकार करते हैं, भारत सरकार को यह भूमिका पसन्द नहीं आई, मैंने उनसे कहा, कि हमारी सरकार को महसूस हुआ कि जनता विमुक्ति मोर्चे की शक्ति बढ़ने से भण्डारनायक सरकार खतरे में पड़ जाएगी जो भारत के राष्ट्र हितों के प्रतिकूल होगा। तब वह इसे गलत क्यों मानते हैं ?

वे मेरे प्रश्न का उत्तर देने में (प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं था) जरा गड़बड़ाये और मुझसे ही पूछने लगे कि भण्डारनायक सरकार के पतन से क्या बिगड़ने वाला है ? इस बात को इतने विस्तार से लिखने का कारण यह है कि हर आदमी राष्ट्रीय हितों की व्याख्या अपनी विचारधारा के अनुरूप करने लगता है। समाजवादियों, इंदिरा गांधी पक्षियों, जन-संघियों और साम्यवादियों के राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण हैं : संक्षेप में यह कि विचारधारा से परे कोई देखना नहीं चाहता।

लोगों का मत है कि विदेश-नीति के सम्बन्ध में विचारधारा का प्रश्न प्रमुखतः साम्यवादी राष्ट्रों में उपस्थित होता है। साम्यवादी नेता उठते-बैठते अन्तर्राष्ट्रीयवाद का उद्धोष करते हैं। इसीलिए यह धारणा बनी लगती है। इसलिए उनके सन्दर्भ में यह प्रश्न निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण है परन्तु श्रीलंका-भारत के उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया है कि यह प्रश्न उन तक ही मर्यादित नहीं है, इसलिए विचार और विदेश-नीति के परस्पर सम्बन्ध को समझना महत्त्वपूर्ण है।

विदेश-नीति पर जरा धीरे-धीरे से विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें विचारधारा का प्रश्न कैसे घुस जाता है। विदेश-नीति के अर्थ कोई भी हेतु हो, उनका एक हेतु विचारधारा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। कोई भी सरकार आर्थिक और सामाजिक तन्त्र की सुरक्षा को विदेश-नीति एक प्रमुख उद्देश्य मानती है। साधारणतया सरकार उस तन्त्र को खतरे में नहीं डालेगी। उस तन्त्र की सुरक्षा का महेंजर खलर ही सरकार समस्याओं से निपटती है।

विकसित राष्ट्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच स्थूल रूप से विदेश-नीति सम्बन्ध मतभेद होते हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दलों में नीति विषयक कोई मुनिग्रिचन और परस्पर भिन्न मत होने की सम्भावना नहीं होती। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वहाँ विदेश-नीति सम्बन्धी कोई मतभेद नहीं होने परन्तु सामान्यतः ये मतभेद विवरण विषयों और नीतियों के क्रियान्वयन सम्बन्धी होते हैं। विषयनाम जैसे मामले पर जो तीव्र मतभेद थे वे किसी विशिष्ट राजनीतिक दल या उसके राजनीतिक तत्वज्ञान की उपज नहीं थे। अनेक बार तो इन मतभेदों का राजनीतिक दलों में कोई सम्बन्ध भी नहीं होता।

इसमें भिन्न दशा भारतीय उपमहाद्वीप के विकासशील देशों की है। इस काँ के क्या कारण हैं। इसका स्पष्ट उत्तर है विचारधारा। अमेरिका जैसे देश में प्रचलित आर्थिक और सामाजिक तन्त्र में दोनों पक्षों के स्वार्थ परस्पर गुंथे हुए हैं। उस तन्त्र में किसी भी प्रकार का प्रातिपक्षी परिवर्तन माने का वायदा कोई दल नहीं करता।

इसके विपरीत दशा हमारे देश की है। इसलिए हमारे यहाँ विदेश-नीति विषयक इतने तीव्र मतभेद हैं। इन मतभेदों की जड़ से हमारे आर्थिक और सामाजिक तन्त्र का निर्माण और विकास होता है।

विचारधारा और विदेश-नीति बाबत दूसरा प्रश्न साम्यवादी राष्ट्रों की विदेश-नीति के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है। ये राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का ढोल चाहे जितनी जोर से पीट रहे हों उनकी विदेश-नीति बहुत अधिक भिन्न नहीं होनी। जब वीयतनाम पर बमबारी हो रही हो तब ब्रेझ्नेव या माओ, निक्सन के साथ शंघैत या माओत्साई (एक प्रश्नात चीनी मछ) का समास्वादन कर सकते हैं। यह कैसे सम्भव होता है? तब 'अन्तर्राष्ट्रीयतावाद' वहाँ तक मारता है?

फिर भी हमें एक अन्तर ध्यान में रखना होगा। युद्धविराम से पूर्व वीयतनाम को सोवियत संघ और चीन की ओर से अचिरित सहायता मिलती रही, वल्कि युद्धविराम के छ महीने पहले तक परस्पर सन्देह से देखने वाले चीन और रूस जैसे राष्ट्रों ने सहायता कार्य में परस्पर सहयोग का उपक्रम किया।

जित प्रकार और जिस वेग से वीयतनाम में मदद पहुँची उन पर विचार करते ही यह सवाल खड़ा होता है कि चीन और सोवियत संघ में वास्तव में कोई संपर्क है या नहीं, यहाँ विचारधारा जो भूमिका अदा करती है उसका खयाल घाता है। सोवियत संघ के भय से अमेरिका से सम्बन्ध जोड़ने वाला चीन और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद आन्दोलन में चीन ने जो सुप्रसिद्ध क्रान्ति की उसकी ओर श्रुता से देखने वाला रूस—इन दोनों में यह सहयोग कैसे सम्भव हुआ? इन दोनों में यह सहयोग कैसे सम्भव हुआ? राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के प्रति वैचारिक साम्य का ही परिणाम है, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में हमें कोई रुचि नहीं है, चीन अभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह कभी भी, किसी भी राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में सहयोग न देगा, इसका कारण भी वैचारिक है।"

मार्शल यह है कि विदेश-नीति में संबंध विचारधारा बाहे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, पर वह एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य घटक है। हमें दृष्टि से मोभल कर देने पर विदेश-नीति का विवेचन अपूर्ण और दिग्भ्रमित हो जाता है।

कुछ प्रमुख विचारधाराएँ

हम कह चुके हैं कि मॉर्गेन्यो ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराओं को तीन मूल्या ध्रेणियों में विभाजित किया है—यथापूर्व-स्थिति की विचारधाराएँ, साम्राज्यवाद की विचारधाराएँ, एवं अस्पष्ट तथा अनेकार्थी विचारधाराएँ। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि साम्राज्यवादी नीतियों पर हमेशा ही विचारधारा का पर्दा डाला जाता रहा है। अग्रिम पतित्यों ने हम मॉर्गेन्यो द्वारा प्रस्तुत विचारधाराओं की विवेचना करेगे और तदुपरान्त प्रजातन्त्र तथा साम्यवाद इन दो विचारधाराओं पर विचार करेगे जो आज समूचे अन्तर्राष्ट्रीय जगत पर छाई हुई हैं।

यथापूर्व-स्थिति (Status-quo) की विचारधाराएँ—यथापूर्व-स्थिति की नीति में विश्वास करने वाला राष्ट्र अपने व्यवहार को विचारधाराओं के आवरण में छिपाना नहीं चाहता। इसका मुख्य कारण यह है कि वस्तु-स्थिति का अस्तित्व होता है और इस आधार पर उसे नैतिक न्यायोचितता प्राप्त हो जाती है। जो वर्तमान है, उसके पक्ष में कुछ तो होना चाहिए, अन्यथा वह वर्तमान नहीं होता।

मार्क्सवादी का कथन है कि जो देश यथापूर्व-स्थिति की नीति अपनाता है वह उस शक्ति की रक्षा का प्रयास करता है जो कि उसको प्राप्त है अतः सम्भव है कि वह किसी को भी अपना शत्रु अथवा मित्र न बनाए। खासतौर पर यह उस समय होता है जबकि उसकी क्षेत्रीय यथापूर्व-स्थिति को कोई कानून या नैतिक चुनौती नहीं दी गई हो और परम्परागत रूप से इस यथापूर्व-स्थिति की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय शक्ति ही अनन्य रूप से प्रयोग में लाई गई हो। स्विट्जरलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन जैसे राष्ट्र अपनी विदेश-नीति को यथापूर्व-स्थिति में रखने वाली नीति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि इनकी यथापूर्व-स्थिति को न्यायोचित मान लिया गया है।

जो देश यथापूर्व-स्थिति को अपनाते हैं वे आवश्यक रूप से शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के समर्थक बन जाते हैं। दूसरी ओर साम्राज्यवादी नीतिवादी यथापूर्व-स्थिति में अव्यवस्था पैदा करके प्रायः युद्ध की ओर अग्रसर होती हैं और युद्ध की सम्भावना को ही वे सदैव ध्यान में रखती हैं। जो विदेश-नीति शान्तिवाद का समर्थन करती है वह साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए यथापूर्व-स्थिति को कायम रखने का पक्ष लेती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आदर्श भी यथापूर्व-स्थिति की नीति के लिए समान सैद्धान्तिक कार्य करता है। कानून सामान्य रूप से और अन्तर्राष्ट्रीय कानून विशेष रूप से एक स्थिर सामाजिक शक्ति है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई किसी विशेष विदेश-नीति के पक्ष में सदैव यथापूर्व-स्थिति की नीति के वैचारिक आवरण के रूप में प्रयुक्त होती है। यथापूर्व-स्थिति की नीति का समर्थन करने के लिए समुक्त राष्ट्रसंघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का भी प्रयोग किया जाता है। यथापूर्व-स्थिति कायम रखने का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का सपोषण समझा जाता है। दोनों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बताकर ही इस नीति के प्रतिपादक अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाते हैं। यह नीति सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की ओर भी प्रेरित हो सकती है क्योंकि यथापूर्व-स्थिति के समर्थक देश बदलने वाले देशों के विरुद्ध संगठित हो सकते हैं। इस नीति की एक अन्य विचारधारा यह है कि छोटे राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा की जाय। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यथापूर्व स्थिति में किए जाने वाले परिवर्तन प्रायः छोटे राष्ट्रों की क्षमता पर ही किए जाते हैं।

साम्राज्यवाद की विचारधाराएँ—साम्राज्यवादी नीति को सदा ही एक विचारधारा की आवश्यकता होती है क्योंकि यथापूर्व-स्थिति की नीति के विपरीत साम्राज्यवाद सदा ही अपने कर्णों पर प्रामाणिकता का भार लेकर चलता है। उसे यह प्रमाणित करना होता है कि वह जितना यथा स्थिति को पकड़ना चाहता है वह पकड़ देने लायक है, और इसके बाद शक्ति का जो नए सिरे में वितरण किया जाएगा

वह नैतिक एवं न्यायपूर्ण होगा। गिवन के शब्दों में, "प्रत्येक युद्ध के लिए मरणाशयवा बढते का, मर्यादा अथवा उत्साह का, अधिकार अथवा उपयुक्तता का उद्देश्य तुरन्त विजेता के कानूनी शब्दकोप में ढूँढ लिया जाता है।"

साम्राज्यवाद की कुछ विचारधाराएँ कानूनी मान्यताओं का भी प्रयोग करती हैं, लेकिन ऐसा करते समय वे वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हवाला नहीं देती। अन्तर्राष्ट्रीय कानून तो स्थायी रूप से वर्तमान यथापूर्व-स्थिति का पोषक होता है जबकि साम्राज्यवाद का चरित्र गतिमान विचारधारा की भाँति करता है। कहा जाना है कि प्राकृतिक कानून का सिद्धान्त साम्राज्यवाद की मंडान्तिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। साम्राज्यवादी राष्ट्र यथापूर्व-स्थिति को पलट देने के भावों से होते हैं, अतः वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अन्यायपूर्ण अथवा अगम्य बताते हुए उससे भी उच्च कानून की बात करते हैं जो न्याय की भाँति को पूरा करता है। प्रायः औपनि-
वेशिक साम्राज्यवाद को ऊँचे-ऊँचे सैद्धान्तिक नारों के आवरण में ढबाने का प्रयत्न किया जाता है। अरब-विस्तार के युग में अरब साम्राज्यवाद को यह कह कर न्यायोचित ठहराया गया कि वह धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक था। नैपोलियन का साम्राज्यवाद यूरोप भर में स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के नाम पर फैला था। इसी प्रकार रूसी साम्राज्यवाद विश्व-शान्ति और पूँजीवादी घेरे के विरुद्ध सुरक्षा के नाम पर फैल रहा है, तो अमेरिकी साम्राज्यवाद साम्यवाद से सुरक्षा और स्वतन्त्र विश्व के हितों की रक्षा के नाम पर फैल रहा है।

मॉर्गेंथो के अनुसार आधुनिक युग में, विशेषकर डार्विन और स्पेंसर के सामाजिक दर्शन के प्रभाव में, साम्राज्यवादी विचारधाराओं ने जीवन-शास्त्रीय तर्कों को प्राथमिकता प्रदान की है। योग्यतम की विजय एवं अस्तित्व के लिए सघर्ष के सिद्धान्तों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में लाद दिया गया है। फलस्वरूप सैनिक शक्ति की दृष्टि से सबल राष्ट्रों को दुर्बल देशों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता है। इस दर्शन के अनुसार, यदि शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों का अस्तित्व नहीं मिटाता अथवा कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र के बराबर होने का प्रयास करना है तो यह बात प्रकृति के विरुद्ध है क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार तो शक्तिशाली एवं योग्यतम की ही विजय होनी चाहिए। साम्राज्यवादी विचारधारा की यह मान्यता है कि शक्तिशाली और योग्यतम राष्ट्रों का स्थान सर्वोच्च है, वह इस धरती पर रहने की भाँति है। इतिहास साक्षी है कि जर्मनी के नाजीवाद, इटली के फासीवाद और जापान के सैनिकवाद ने अपने समर्थन में जीवन-शास्त्रीय तर्कों का सहारा लिया और कहा कि प्रकृति ने उन्हें विश्व का स्वामित्व करने के लिए भेजा है, लेकिन कमजोर राष्ट्रों की चालाकी और हिंसा के कारण वे अपने निश्चित पद पर नहीं हैं।

मॉर्गेंथो के अनुसार साम्राज्यवाद का सबसे प्रचलित आवरण और दोषमुक्ति का स्रोत जो व्यवहार में लाया गया है, वह है साम्राज्यवाद-विरोधी विचार-पद्धति अर्थात् साम्राज्यवादी अपने व्यवहार को न्यायोचित सिद्ध करने और अपनी महत्वा-
कांक्षा पर पर्दा डालने के लिए साम्राज्यवाद-विरोधी विचारधारा का जामा पहनते

हैं। साम्राज्यवादी देश यह सिद्ध करता है कि दूसरे देश शक्ति-प्राप्ति की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अपनी नीतियों को संचालित कर रहे हैं जबकि उसकी स्वयं की नीति शुद्ध रूप से आदर्श उद्देश्यों से प्रेरित है। पिछले दोनो महायुद्धों में भाग लेने वाले दोनों पक्षों का दावा था कि वे दूसरे पक्ष के साम्राज्यवादी विस्तार के विरुद्ध अपनी रक्षा कर रहे हैं। सन् 1941 में रूस पर आक्रमण करते समय जर्मनी ने कहा था कि वह रूसी साम्राज्यवादी इरादों को तोड़ने के लिए ऐसा कर रहा है। महायुद्धोत्तर युग में साम्यवादी और गैर-साम्यवादी दोनों ही पक्षों की विदेश-नीतियाँ स्वयं को साम्राज्यवाद-विरोधी घोषित करती हैं और एक-दूसरे पर साम्राज्यवादी होने का आरोप लगाती हैं जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों ही साम्राज्यवादी आकांक्षा से परिपूर्ण हैं। दोनों पक्षों में प्रादेशिक साम्राज्यवाद की भी मूल है और आर्थिक साम्राज्यवाद की भी।

अनेकार्थक एवं अस्पष्ट विचारधाराएँ—मॉर्गेंथो के अनुसार साम्राज्यविरोधी विचारधाराएँ अपनी स्पष्टता और अनेकार्थकता से ही प्रभावी होती हैं। वे निरीक्षण-कर्त्ता की शक्कर में डाल देती हैं जो यह निश्चय नहीं कर पाता कि वह साम्राज्यवादी विचारधारा का अध्ययन कर रहा है अथवा यथापूर्व-स्थिति की नीति के वास्तविक रूप का निरीक्षण कर रहा है। ऐसा प्रायः तब होता है जब एक विचारधारा किसी विशेष नीति को समर्थित करने के लिए नहीं अपनाई जाती और उसे यथापूर्व-स्थिति तथा साम्राज्यवाद दोनों के समर्थकों द्वारा अपना लिया जाता है। उदाहरण के लिए, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में शक्ति-सन्तुलन की यथापूर्व-स्थिति और साम्राज्यवाद दोनों के समर्थकों द्वारा एक सैद्धान्तिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया। वर्तमान काल में राष्ट्रीय आत्म-निर्णय तथा समुक्त-राष्ट्रसंघ की विचारधाराएँ भी यही कार्य सम्पन्न कर रही हैं। शीत-युद्ध के आरम्भ से निरन्तर विकसित होती हुई ये विचारधाराएँ शान्ति की विचारधारा से समुक्त हो गई हैं।

मॉर्गेंथो ने अनेकार्थी एवं अस्पष्ट विचारधाराओं की पुष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के आधार पर वैदेशिक दमन से केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोप की राष्ट्रीयताओं की स्वतन्त्रता को उचित ठहराया गया था। सैद्धान्तिक स्तर पर यह केवल साम्राज्य की यथापूर्व-स्थिति के विरोध में ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद के विरोध में था फिर भी आत्म-निर्णय के नाम पर ही पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्था के विनाश के तुरन्त बाद नए साम्राज्यवाद का जन्म अवश्यम्भावी हो गया। पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया तथा यूगोस्लाविया के उदाहरण उतने ही विलक्षण थे जितने वे आवश्यक थे, क्योंकि पुराने साम्राज्यवादी ढाँचे के ढह जाने से उत्पन्न शक्ति-शून्यता की पूर्ति करना जरूरी था। पर जैसे ही नए स्वतन्त्र राष्ट्र शक्ति-सम्पन्न हुए, वैसे ही उन्होंने भी उसी राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त की नई यथापूर्व-स्थिति की रक्षा के लिए प्रयोग किया। प्रथम महायुद्ध के अन्त से लेकर द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक यह सिद्धान्त उनका सबसे शक्तिशाली वैचारिक अस्त्र रहा।

हिटलर ने अपने प्रचार-कार्य के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर करारी चोट की ताकि वह अपनी प्रादेशिक प्रसार-नीतियों को छिपा कर उनकी उचित ठहरा सके। चेकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड में रहने वाले जर्मन अल्प संस्रक, राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के झण्डे के नीचे इन देशों के राष्ट्रीय अस्तित्व को मिटाने के लिए बड़ी कार्य करने लगे जो चेकोस्लोवाक और पोलिश राष्ट्रीयताओं ने इसी सैद्धान्तिक झण्डे के नीचे आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्यवाद को मिटाने के लिए किया था। इस प्रकार वर्साय सन्धि की यथापूर्व-स्थिति से लाभान्वित होने वाले देशों का सैद्धान्तिक हथियार उन्हीं के विरुद्ध उपयोग में आया और जब उनके पाम यथापूर्व-स्थिति की रक्षा करने के लिए कोई विचारधारा न रही, तो वे कानून और व्यवस्था की दुहाई देने लगे। चेकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में जो म्यूनिख-समझौता हुआ उसमें भी राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का सिद्धान्त उलझा हुआ था।

मोंटेन्गो का मत है कि संयुक्त-राष्ट्रसंघ की विचारधारा को भी अनेकार्थकता और अस्पष्टता का जामा पहनाया गया है। उन्हीं के शब्दों में, “अपने जन्म से ही संयुक्त-राष्ट्रसंघ को, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा संयुक्तराज्य व उनके मित्र राष्ट्रों के लिए उनकी द्वितीय महायुद्ध की विजय के उपरान्त स्थापित यथापूर्व-स्थिति की रक्षा के यन्त्र के रूप में सशक्ति किया गया था। परन्तु द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद के वर्षों में ही यह दृष्टिगोचर होने लगा कि यह यथापूर्व-स्थिति केवल अस्थायी तथा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा लिए गए विरोधी दावों व व्याख्याओं से ग्रस्त है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ की विचारधारा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी विशेष व्याख्याओं को न्यायसंगत प्रमाणित करने तथा अपने विशेष दावों के समर्थन के प्रयोग में लाई जाती है। प्रत्येक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघ का पूर्ण समर्थक दृष्टिगोचर होता है और सभी राष्ट्र अपनी विशेष नीति के पक्ष में चार्टर की धाराओं की दुहाई देने हैं। इन नीतियों के विरोधाभासी होने के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ का सन्दर्भ अपनी स्वयं की नीति को न्यायसंगत प्रमाणित करने के लिए और साथ ही साथ उन नीतियों के वास्तविक चरित्र को छिपाने के लिए एक वैचारिक साधन बन जाता है, क्योंकि यह दुहाई साधारणतः मानवाय सिद्धान्तों के आवरण में दी जाती है। उसकी अस्पष्टता ही इस विचार-पद्धति का एक ऐसा साधन बन जाती है जिसके द्वारा अपने अद्भुतों को भ्रम में डाल दिया जाता है तथा मित्रों को शक्ति प्रदान की जाती है।”

द्वितीय महायुद्ध के बाद से शान्ति की विचारधारा ने भी अधिकाधिक मात्रा में इसी प्रकार का कार्य सम्पन्न किया है। आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण युद्ध का स्वरूप इतना विध्वंसकारी बन गया है कि कोई भी देश अपनी विदेश-नीति पर अपनी जनता तथा अन्य देशों का समर्थन तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उसका ध्येय शान्तिपूर्ण है। अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए उन्हें ‘शान्ति-विरोधी’, ‘शान्ति-घाती’ एवं ‘शान्ति-विध्वंसक’ आदि बहने का रिवाज हो गया है। आज शान्ति की दुहाई देना और अपने उद्देश्यों को शान्तिपूर्ण बताना विलकुल अर्थहीन बन गया है क्योंकि कोई

भी देश शान्तिवादी विदेश-नीति को आज इसलिए नहीं अपनाता कि उसे शान्ति से स्नेह है वरन् इसलिए अपनाता है कि वह युद्ध छेड़ कर जोखिम नहीं लेना चाहता। वर्तमान युद्ध की अव्यवस्थित विध्वंसकता के कारण प्रत्येक देश अपनी विदेश-नीति के लक्ष्यों को शान्तिपूर्ण साधनों से ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। किन्तु फिर भी शान्ति का नाम लेकर एक देश दो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्य करता है—प्रथम, वह अपनी वास्तविक नीति के उद्देश्यों को छिपाना चाहता है; और दूसरे, वह अपनी नीतियों के लिए सर्वत्र सद्भावना प्राप्त करना चाहता है।

प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा—जो विचारधारा एक संगठित आन्दोलन द्वारा समर्थित होती है अथवा राजनीतिक सत्ता का रूप ले लेती है उसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर अधिक होता है। कुछ विचारधाराएँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से दूर वा रिश्ता रखती हैं, उनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत उनके जो ऐसे मूल्यों को अभिव्यक्त करती हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। आज के युग में प्रजातन्त्रात्मक और साम्यवादी—ये दो विचारधाराएँ सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को आच्छादित किए हुए हैं। ये दोनों परस्पर-विरोधी हैं और विरोधी लक्ष्यों की पूर्ति का साधन बन रही हैं।

प्रजातन्त्र की मौलिक संरचना में कुछ केन्द्रीय विश्वास होते हैं जिनकी साधना में सलग्न व्यवस्था ही प्रजातन्त्रात्मक मानी जा सकती है और जो व्यवस्था इन विश्वासों के मार्ग में बाधक बनती है उसे अप्रजातन्त्रात्मक माना जाता है। मानव-व्यक्तित्व की महत्ता, जनता की स्वीकृति से शासन, न्याय का सम्बर्द्धन, कानून के शासन की स्थापना, आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक न्याय की स्थापना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, सार्वभौम मानव-अधिकारों की व्यवस्था आदि मान्यताएँ प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था के मूल में विद्यमान हैं। ये विश्वास एक प्रजातन्त्र के राजनीतिक जीवन का स्वरूप निर्धारित करते हैं। सध्यों के समायोजन को शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा संवागत रूप देने में प्रजातन्त्र का मौलिक योग माना जाता है। प्रजातन्त्र की यह विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डालती है। समानता का आदर्श केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता क्योंकि प्रजातन्त्र तो मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास करता है। प्रजातन्त्रात्मक आदर्शों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करते समय अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ प्रायः इसीलिए उत्पन्न होती हैं कि राष्ट्रीय सीमाओं के बाह्य सामाजिक एकात्मता और मजबूती नहीं रहती, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समझौतों की तकनीकें जटिल होती हैं एवं राष्ट्रीय एकात्मता की प्रक्रिया हर देश में चलती रहनी है। श्लीचर महोदय का यह अभिमत सही है कि चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन असमानता-विरोधी प्रजातन्त्रात्मक आदर्शों को प्रजातन्त्रात्मक सरकारों और जनता द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने में कठिनाई होती है।

प्रजातन्त्रात्मक आदर्शों की राष्ट्रवाद के साथ भी कुछ भ्रमंगति बताई जानी है। प्रथम, प्रजातन्त्र व्यक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य मानता है तथा राज्य को मानव-व्यवस्था

का साधनमात्र समझता है जबकि राष्ट्रवाद राज्य को सर्वोच्च मूल्य प्रदान करता है। द्वितीय, प्रजातन्त्र हर जगह व्यक्ति की अधिकाधिक स्वतन्त्रता का पोषक है और स्वतन्त्रता के मार्ग में प्रत्येक बाधा का विरोध करता है, जबकि राष्ट्रवाद व्यक्ति को राज्य के अधीनस्थ बना देता है और राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर अत्यधिक बल देते हुए प्रत्येक हस्तक्षेप का विरोध करता है, चाहे वह प्रजातन्त्र के अनुकूल हो या नहीं। इस प्रकार राष्ट्रवाद और प्रजातन्त्र दोनों अपने विशुद्ध रूप में साथ-साथ नहीं चल सकते। समाधान के लिए मुझसे दिया जाता है कि मानव-अधिकारों के विषय को राज्यों के क्षेत्राधिकार से निकाल कर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का विषय बना दिया जाए। प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। साम्राज्यवादी व्यवस्था को प्रजातन्त्रात्मक केवल तभी बनाया जा सकता है जब निर्णय-प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा के प्रभाव का विश्लेषण करने पर बिदित होगा कि यह अनेक प्रकार से इसके व्यवहार का स्वरूप-निर्धारण करती है। प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रजातन्त्रात्मक व्यवहार जातीय, आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर की ओर ध्यान दिए बिना ही सभी व्यक्तियों के कल्याण का प्रयास करता है। प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा की मान्यता है कि किसी भी देश का कल्याण हमारे देश के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, एक को दबा कर दूसरे को उठाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। हमारे, व्यक्तिगत सम्मान और गरिब की अभिवृद्धि में हर सम्भव योगदान किया जाएगा तथा इस पर देश के नागरिकों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामान्य मानव-जानि की दृष्टि से विचार किया जाएगा। तीसरे, मानव-अधिकारों और मूल्यों की रक्षा के मार्ग में सम्प्रभुता बाधक नहीं बनेगी। चौथे, उन संस्थाओं की स्थापना में सहयोग दिया जाएगा जो व्यक्तियों को शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा उन महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने का अवसर प्रदान कर सकें जो कि उनके हितों और मूल्यों को प्रभावित करते हैं। समान व्यक्तियों द्वारा असमान शक्तियों के उपयोग को रोका जाएगा। उपनिवेशवाद के प्रत्येक रूप का विरोध होगा। पाँचवें, सभी ऋणों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए उपयुक्त एवं अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा तथा बहुमत के आधार पर शान्तिपूर्ण परिवर्तन लाया जाएगा। अपनी इन्हीं विशेषताओं के बल पर प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करती है। कुछ विचारकों का तर्क है कि प्रजातन्त्रात्मक मूल्यों की प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना उपयोगी रहेगा या नहीं, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मानव-इतिहास में अत्याचारों के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो सद्-उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए थे। प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोणीय और व्यवहारों के प्रति सहनशील होता है और सभी सत्यों को सन्देहशील की दृष्टि से देखता है, यहाँ तक कि स्वयं के सत्य पर भी उसे पूरा विश्वास नहीं होता।

साम्यवादी विचारधारा—साम्यवाद की प्रकृति मूल रूप से सत्तावादी है, अतः प्रजातन्त्र की तुलना में इसका स्वरूप अधिक स्पष्ट है। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन,

माओ आदि ने साम्यवादी विचारधारा की व्याख्याएँ की हैं। इसकी आधारभूत मान्यताओं में प्रथम यह है कि इतिहास एक निरन्तर संघर्ष की कहानी है और वर्ग-संघर्ष में साम्यवाद की प्रगतिशील शक्तियाँ अन्ततोगत्वा पूँजीवादी शक्तियों को समाप्त कर देंगी। दूसरे साम्यवाद और उदार सांविधानिक प्रजातन्त्र के बीच मूलभूत संघर्ष है जिन्हें केवल साम्यवाद की अन्तिम विजय द्वारा ही मिटाया जा सकता है। तीसरे, एक वर्गहीन समाज की रचना अनिवार्य है और अन्तिम रूप से राज्य-संस्था की समाप्ति करनी होगी। चौथे, श्रमिक वर्ग की तानाशाही लानी होगी, सभी देशों में साम्यवाद स्थापित करना होगा और एकमात्र साम्यवादी दल की पूर्ण आजाकारिता ही ठीक है। पाँचवें, शक्ति एवं शक्ति-संघर्ष तथा क्रान्ति से ही साम्यवाद को सार्वभौमिक बनाया जा सकेगा। लेनिन, स्टालिन, माओ आदि ने मुरप रूप से शक्ति प्राप्त करने तथा एकीकृत करने की रणनीति और तकनीक की व्याख्या की है। छठे, साम्यवादी विचारधारा की मान्यता है कि गैर-साम्यवादी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए, विरोधियों के आपसी विरोधों का लाभ उठाने के लिए तथा क्रान्तिकारी दशाओं को प्रोत्साहन देने के लिए साम्यवादी आन्दोलनकारी कोई भी साधन अपना सकते हैं। साम्यवादी विचारधारा में साम्यवादी दल की शक्ति के एकाधिकार को सैद्धान्तिक आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है। साम्यवाद के प्रचार-प्रसार का बड़ा सोवियत रूस ने उठाया हुआ था तथापि अब रूस और लाल चीन दोनों मैदान में हैं। साम्यवादी जगत् के नेतृत्व के लिए दोनों में प्रतिस्पर्धा है जिसके लिए सैद्धान्तिक संघर्ष भी पैदा किए गए हैं। रूस और चीन के सैद्धान्तिक संघर्षों का विस्तार से विवेचन पुस्तक के अगले अध्याय में किया गया है। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि साम्यवादी विचारधारा आज दो भागों में विभाजित हो गई। सोवियत संघ शान्तिपूर्ण महत्त्वपूर्ण बात करने लगा है और यह सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील है कि स्टालिन की आत्ममंथनकारी नीतियों को त्याग दिया गया है। इसके विपरीत चीन सोवियत रूस को 'सशोधनवादी' की सजा देते हुए उसे साम्यवाद के लक्ष्य से पीछे हटना हुआ मानता है और रूस को पूँजीवादी शक्तियों के सामने 'कायर' की सजा देता है।

साम्यवादी विचारधारा जिस रूप में साम्यवादी राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करती है उसे निर्धारित करना बड़ा कठिन है। विभिन्न समयों और स्थानों पर इसके अर्थ अलग-अलग रहे हैं तथापि कुछ ऐसे सामान्य तत्त्व हैं जिन्हें महत्वपूर्ण माना जा सकता है। साम्यवादी-दर्शन विश्व की घटनाओं को देखने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह विचारधारा यह मानकर चलती है कि इतिहास कुछ ऐतिहासिक वानुओं पर आधारित है जिन्हें भौतिक दशाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। सत्ताएँ तथा मस्तिष्क और कुछ भी नहीं हैं, केवल मामूली विश्वास के एक विशेष स्तर पर पाई जाने वाली भौतिक दशाओं की ही अभिव्यक्ति मात्र है। यद्यपि व्यक्ति ऐतिहासिक परिवर्तन के मूल रूप को नहीं बदल सकता, किन्तु यह अपरिहार्य को मोघ्र ला सकता है।

साम्यवाद की विचारधारा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा-नों का हित-साधन मुख्य उद्देश्य है। इसलिए साम्यवादियों को हर जगह नैतिक, प्राकृतिक एवं प्रगतिशील कर्तव्यों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद को मुख्य म्यान देना चाहिए तथा सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी राज्यों के हितों की साधना करनी चाहिए न कि अपने पूँजीवादी स्वामियों की। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार ऐसा करके वे साम्यवाद के उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसकी साधना के लिए वर्तमान साम्यवादी विचारधारा सच्चे रूप में अन्तर्राष्ट्रीय है जिसका आधार वर्गवाद है। राष्ट्रवाद के लिए यह जो भी छूट प्रदान करती है वह अस्वाभी है तथा इसकी रक्षणीति है।

विचारधारा सम्बन्धी अनुमन्वान की समस्याएँ

इसमें कोई सन्देह नहीं कि विचारधारा सम्बन्धी विविष्ट समस्याओं पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है (उदाहरणार्थ चीन और रूस का विवाद ही लिया जा सकता है)। हितों के साथ विचारधाराओं का क्या सम्बन्ध है और मंडान्तिक नीतियों पर विचारधाराओं का कितना प्रभाव पड़ता है, इस सम्बन्ध में सामान्य और मौलिक प्रश्न ही नहीं, आवश्यक विश्लेषण और अपेक्षित अनुमन्वान भी हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में, केवल राष्ट्रीय हितों या समस्त राष्ट्रों के राजनीतिक हितों पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के अन्तर्गत सभी उपवर्गों के आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार के विशेष हितों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी स्थान या काल विशेष में, किसी वर्ग, गुट या राष्ट्रीय हित विशेष के साथ, किसी विशिष्ट विचारधारा के सम्बन्ध में, यदि ध्यानपूर्वक और विस्तार के साथ अध्ययन किया जाए तो वह राष्ट्रीय हितों तथा बृहत् विचारधाराओं के मध्यवर्ती कारण और प्रभाव सम्बन्धी अटकलों की अपेक्षा निश्चय ही अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

यदि हम और भी दारीकी में जाना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें निम्नलिखित अनुसन्धान क्षेत्रों में अवगाहन करना पड़ेगा, विशिष्ट विचारधाराओं पर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, उदाहरणार्थ—शक्ति की नई धुरियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, उदाहरणार्थ—शक्ति की नई धुरियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अनेक वीणाएँ धुरीकरण के स्थान पर, द्विध्रुवीकरण की प्रक्रिया तथा प्रमुख विचारधाराओं पर इस प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव, विभिन्न विचारधाराओं की अन्योन्य क्रिया, उदाहरण के लिए उदार लोकतन्त्रीय शासन के विशेष में सर्वाधिकारी शासन। इस सम्बन्ध में हमें यह भी अन्वेष्ट करना पड़ेगा कि आग जनता किस सीमा तक अपने नेताओं की विचारधाराओं से सहमत और प्रभावित होती है तथा वे नेता अपनी नीति विशेष के प्रति किस प्रकार सैद्धान्तिक समर्थन प्राप्त करते हैं? नेताओं और राष्ट्रीय हितों की निर्धारण प्रक्रिया में, विचारधाराओं का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? इसके अनिश्चित यह भी हमें देखना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय विचारधाराओं की 'प्रकार विद्या' के सम्बन्ध में किस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता है?

इस प्रकार के विश्लेषण का प्रभाव नीतियों पर भी पड़ेगा। विचारधाराओं के अध्ययन से, अन्य व्यक्तियों के 'पदों' को समझने में सहायता मिलेगी और वे स्वयं अपने 'पदों' को भी समझ सकेंगे। इस प्रकार पश्चिम के देश यह देखेंगे कि अब साम्यवादी देशों की नीतियों का आधार, आंशिक रूप में भले ही सही हो, पर उसका आधार भय ही है, उनकी अन्तर्निहित आक्रमकता नहीं। इसी प्रकार साम्यवादी देश भी यह जान पाएँगे कि उनके बारे में पश्चिमी देशों की पूर्व-धारणा का कारण पश्चिमी प्रेक्षकों द्वारा यह देखा जाता है कि साम्यवादी देशों में विचारधाराओं का महत्व दिन-प्रति-दिन कम होता जा रहा है। इस प्रकार निश्चय ही विदेश नीति पर, विचारधाराओं का प्रभाव कम होगा, जिसके फलस्वरूप उनके भावनात्मक प्रभाव तथा लक्ष्य के प्रति निष्ठावाला रूप क्षीण हो जाएगा। इससे अपने हितों के लिए संघर्षजन्य तनाव दूर होगा तथा ऐसी स्थिति पैदा हो सकेगी, जिसके अन्तर्गत विचारधाराओं के पारस्परिक संघर्ष की अपेक्षा, समझदारी और अधिक धारानी से समझौता हो सकेगा। संहारक अणु-शस्त्रों ने, समस्त मानव-जाति को जिस खतरे में डाल दिया है, उसकी अनुभूति मात्र से विचारधारा का महत्व घटने में सहायता मिलेगी, जैसा कि सोवियत संघ की नीति से स्पष्ट होता है। इस प्रक्रिया से एक ऐसा सत्य सन्देश प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो सभी देशों पर लागू हो सके। विचारधाराओं के प्रभाव के घटने के साथ-ही-साथ सच्चे सिद्धान्तों तथा शान्ति के वातावरण का उदय होगा ऐसी सदाशयी आशा तो आज भी की जा सकती है।¹

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल्य और दृष्टिकोण (Values and Attitudes in International Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए यह मान कर चलना चाहिए कि मानव-समूहों में अनेक दृष्टिकोण, विश्वास एवं मूल्य पाए जाते हैं। मनुष्य भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौतिक वातावरण में रहते हैं। वातावरण की इन विशेषताओं द्वारा ही यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति का मित्र अथवा शत्रु कौन होगा। व्यक्ति अपने उपलब्ध साधनों की सीमा को भी जान लेता है जिनके साथ रहने के लिए समायोजन करना जरूरी है। राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य तथा सहयोग को परम्पराएँ इसी पृष्ठभूमि में विवक्षित होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यह विचार किया जाना जरूरी है कि व्यक्ति कुछ मूल्यों को क्यों अपनाता है और अन्य सत्त्वृति तथा शक्तियों के प्रभाव में वह उन्हें कैसे बदल लेता है। एक राष्ट्र के लोगों के दृष्टिकोणों, मूल्यों एवं उद्देश्यों की समानता यह निर्धारित करती है कि उनके बीच विभिन्न प्रश्नों पर कितना मतभेद रहेगा। इससे राजनीतिक संस्थाओं को स्थायित्व प्राप्त होता है। जिन देशों के मूल्य और दृष्टिकोण एक समान हो जाते हैं, उनके बीच सहयोग, शान्ति एवं विचार-विमर्श

की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर जहाँ दृष्टिकोण और मूल्यों में भारी प्रसमानता रहती है, वहाँ सम्बन्धों में अस्थिरता एवं समर्थ पाया जाता है।

विभिन्न राज्यों की जनता और नेता अनेक विषयों पर अपना मत निर्धारित करते हैं और यह मत उनके अन्तराष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करता है। शान्ति, युद्ध, साम्राज्यवाद, जातिवाद, पूँजीवाद, अणु-अस्त्र एवं विदेशी सहायता आदि विषयों पर एक राज्य के लोग तथा नेताओं का जो दृष्टिकोण होता है, वही उनकी विदेश-नीति को तय करता है। यह दृष्टिकोण उनके मूल्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह मूल्य-व्यवस्था ही तय करती है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह राज्य क्या साधन अपनाएँ। अतीत के अनुभव से इन दृष्टिकोणों एवं प्रतिक्रियाओं के निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है।

दृष्टिकोण वास्तविकता को प्रकट कर सकते हैं अथवा उसे घोभल बना सकते हैं। व्यक्ति की प्रक्रिया उसके वातावरण द्वारा निर्धारित होती है। यदि व्यक्ति का ज्ञान यह कहता है कि पृथ्वी चपटी है तो वह उस-उस जगह पर अपनी नाव नहीं चलाएगा जहाँ कि उसके मतानुसार किनारा है। इस प्रकार वाल्टर लिपमैन ने यह ठीक ही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह उसके प्रत्यक्ष या निश्चित ज्ञान पर आधारित न होकर उन चित्रों पर आधारित होता है जो उसने स्वयं बनाए हैं अथवा उसे दिए गए हैं।¹

संसार को वस्तुगत रूप से देखने में दो चीजें हमारी योग्यता को सीमित करती हैं। पहली से तो व्यक्ति की तथ्यों को जानने की क्षमता सीमित होती है। उसका ज्ञान अपूर्ण होता है और तथ्यों के समझने की उसकी योग्यता, समय, अनुभव, सम्पर्क एवं कुशलता के अभाव के कारण सीमित रहती है। लिपमैन के कथनानुसार हमारे मन को एक व्यापक क्षेत्र से सम्पर्क रखना होता है, बहुत शीघ्र ही वस्तु-स्थिति का पता लगाना होता है तथा इतनी सारी चीजें देखनी होती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में हमें बहुत कुछ दूसरों के द्वारा कही गई बातों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। यह समस्या उस समय और भी कठिन बन जाती है जबकि समान तथ्यों द्वारा दो व्यक्ति निर्धारित कार्य के सम्बन्ध में विरोधी निष्कर्षों पर पहुँचते हैं।

सीमा निर्धारित करने वाली दूसरी बात अत्यन्त अस्पष्ट एवं उलझी हुई है। यह अनेक मनोवैज्ञानिक दृष्टियों का संयोग है। वास्तविकता को पहचानने की हमारी योग्यता, हमारे ज्ञान और दुराग्रह, हमारे पहले के प्रतीक एवं हमारे तरीकों द्वारा सीमित होती है। व्यक्ति ने दुनिया के बारे में जो स्वयं की मान्यताएँ बना रखी हैं वह अपने सीमित ज्ञान को उन्हीं से बैठाने की सोचता है। व्यक्ति की पूर्ण मान्यताएँ एक प्रकार से सुरक्षा-यन्त्र का काम करती हैं और वह दुनिया की तस्वीर को इस रूप में देखता है जिस रूप में वह उसकी मान्यताओं के अनुसार निर्धारित हो चुकी है।

व्यक्ति के मस्तिष्क में यह शक्ति है कि वह अपने ही विचारों और कार्यों के उद्देश्यों को धिया सकता है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए मनोविश्लेषण का महत्त्व बढ़ जाता है। राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण वे होते हैं जिनको अपरिवर्तनीय प्रतिमाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वे निर्णय होते हैं जिनको एक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में समर्थ होने से पहले ही दूसरों से प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति जब विचार करता है तो उसके सामने ऐसे अनेक अपरिवर्तनीय 'स्टीरियो टाइप्स' होते हैं जैसे 'फ्रांसीसी', 'सैनिक मस्तिष्क', 'विदेशी', 'बोल्शेविक', 'युद्ध-प्रेमी' आदि। इन शब्दों का अपना एक विशेष अर्थ होता है। इन अपरिवर्तनीय प्रतिमाओं को तर्कपूर्ण मतों के स्थान पर रखा जाता है। व्यक्ति उन चीजों को तुरन्त ग्रहण कर लेता है जो उसकी संस्कृति ने पहले से ही परिभाषित की हुई हैं। ये प्रतिमाएँ व्यक्तिगत जीवन की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी होती हैं।

विदेशियों तथा उनके लक्ष्यों के प्रति अविश्वास रहना लोगों की परम्परागत विशेषता है। इसमें वे लोग अधिक विश्वास करते हैं जो विदेशी शासन या शोषण के शिकार रहे हैं अथवा हैं। एशिया और अफ्रीका के देशों में जो तटस्थता की नीति अपनायी जा रही है उसका कारण केवल यह नहीं है कि ये देश युद्ध को टालना चाहते हैं अथवा महाशक्तियों के युद्ध में तटस्थ रहना चाहते हैं। इस नीति की जड़ों में उन पश्चिमी शक्तियों से स्वतन्त्र रहने की कामना है जिन्होंने अतीत काल में एशिया और अफ्रीका पर शासन तथा उसका शोषण किया था। अब ये देश पश्चिमी प्रभाव का विरोध करने के लिए राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। आज संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रति लेटिन अमेरिका का दृष्टिकोण डर और ईर्ष्या से पूर्ण है। इसका आधार अतीत काल में संयुक्तराज्य अमेरिका के हस्तक्षेप तथा उसके कुछ व्यावसायिक व्यवहार है। ये मतभेद और विरोध केवल ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ही नहीं पनपते बल्कि विभिन्न संस्कृतियों एवं सामाजिक रूपों पर आधारित भिन्न मूल्यों के कारण भी बढ़ते हैं।

दुराग्रह और प्राथमिकताएँ (Prefudiros and Preterences) भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करती हैं। पश्चिमी राज्यों ने घनिष्ठ पारस्परिक राजनीतिक एकाता विकसित कर ली है उनकी सामान्य सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्पराएँ हैं। उनके मूल्यों तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी पर्याप्त एकरूपता देखने को मिलती है। दूसरी ओर साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश समाज की प्रकृति के सम्बन्ध में विरोधी मान्यताएँ लेकर चलते हैं। वे आपस में भी मतभेद रख सकते हैं जैसा कि सोवियत संघ और चीन के बीच पाया जाता है। जिन राज्यों के बीच इन विषयों पर मूल अन्तर रहते हैं, उनमें मैत्री एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की कल्पना नहीं की जा सकती। उनका कोई समझौता अधिक दिनों तक नहीं टिकता।

यह कहा जाता है कि सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का मूल आधार 'वे बनाम हम' की भावना है जो सामूहिक जीवन से प्रभावित होती है। राष्ट्रवाद का विचार, प्राधुनिक संचार-साधन, ऐतिहासिक परम्पराएँ तथा अन्य वैज्ञानिक तत्त्व भी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। प्रजातन्त्रीय समाजों में ये तत्त्व सरकार को अधिक प्रभावित कर विदेश-नीति के सम्बन्ध में उसकी स्वतन्त्रता को सीमित कर सकते हैं।

जो राज्य अपने पड़ोसियों की ओर से मुरझित अनुभव करते हैं, वे प्रायः अपने मनभेदों को शान्तिपूर्ण साप रों से सुलझा देने हैं, किन्तु जब किसी राज्य के हिनो की चुनौती दी जाती है और चुनौती देने वाले राज्य के साथ उसके सहयोग का कोई इतिहास या परम्परा नहीं होती, तो उनके मतभेदों को मिटाना बड़ा कठिन बन जाता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की एक लम्बी परम्परा है और इसलिए उनको पारस्परिक प्रबन्ध करने में पर्याप्त सुविधा रहती है। दूसरी ओर रूस और टर्की के बीच यद्यपि औपचारिक सम्बन्ध हैं, तथापि टर्की के वर्ग पर नियन्त्रण के लिए प्रतियोगिता के इतिहास ने टर्की को रूसी उद्देश्यों के प्रति सन्देहशील बना दिया है। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक है तथा उसने नाटो की सदस्यता स्वीकार की है। भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग की सम्भावनाएँ कश्मीर विवाद के कारण असम्भव बन गई हैं।

नैतिकता और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (Morality and International Politics)

नैतिक एवं कानूनी व्यवस्थाएँ मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार को नियमित करती हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति पर दूसरे के अधिकारों का आदर करने का कर्तव्य डालकर सभी को स्वतन्त्रता में वृद्धि करती हैं। यदि नैतिक मापदण्ड पूरी तरह से प्रभावशाली रहे तो कानून अनावश्यक बन जाएँगे। नैतिक आचार-संहिता सदैव ही कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करती है। केवल तानाशाह ही मात्र कानून द्वारा प्रशासन कर सकता है। हम समाज उसी को कहते हैं जो अच्छाई-बुराई के सम्बन्ध में एकमत होता है तथा दूसरे के अधिकारों का आदर करता है। जो समाज सामान्य मापदण्ड नहीं रखता उसमें नैतिक दृष्टिकोणों पर थोड़ा ही समझौता रहता है। एक सच्चा समाज वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य प्रायः समान होते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का स्वामी या सेवक नहीं होता। आज हम जब 'अन्तर्राष्ट्रीय समाज' शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह वास्तविकता की अपेक्षा एक वांछनीय आशा मात्र प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इकाइयों की समानता का तत्त्व नहीं पाया जाता। अन्तर्राष्ट्रीय समाज (International Community) जैसी कोई चीज न होने की वजह से ही यह कहा जाता है कि एक राज्य के अधिकारों को दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार में नैतिक नियमों के अनुसार चलना चाहिए।

नैतिकता की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। नैतिकता की न तो कोई सर्वमान्य परिभाषा है और न ही इसका कोई सर्वमान्य व्यवहार है। व्यवहार के नैतिक मापदण्ड प्रत्येक संस्कृति एवं सम्यता में भिन्न-भिन्न होते हैं। एक देश की

सम्बन्धिता तथा संस्कृति में जो मापदण्ड तथा मूल्य प्रचलित हैं उनको दूसरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता। संयुक्तराज्य अमेरिका में जिस चीज को आदर्श माना जाता है, यह जरूरी नहीं है कि अफ्रीका और एशिया के देशों में भी उसे आदर्श माना जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नैतिकता का वही अर्थ नहीं होता जो व्यक्तिगत सम्बन्धों में हुआ करता है। एक देश के नेता जब विदेश-नीति के सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं तो वे अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्डों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश अपनी विदेश-नीति के लक्ष्यों को नैतिक तथा मानवीय सिद्ध करने का प्रयास करना है। प्रायः सही आचरण को नैतिकता कहा जाता है, किन्तु सही आचरण वास्तव में क्या है, यह जानना बड़ा कठिन है। एक स्थिति में जो आचरण एक व्यक्ति विशेष की दृष्टि से सही है, वही आचरण अन्य स्थिति में उनके लिए अथवा उसी स्थिति में अन्य व्यक्ति के लिए अनैतिक हो सकता है। नैतिकता के सम्बन्ध में अनेक विचार हैं। इनमें से मुख्य दो ये हैं—

1. कुछ लेखक यह मानते हैं कि एक सार्वभौमिक नैतिक मापदण्ड होता है और वही कार्य नैतिक कहा जा सकता है जो उसके अनुरूप हो। नैतिकता का मापदण्ड केवल एक ही होता है, अनेक नहीं। व्यक्ति यह जान सकता है कि नैतिक मापदण्ड उससे किस प्रकार के व्यवहार की आशा करता है। यह नैतिक मापदण्ड सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है चाहे वे कुछ भी कार्य करते हों। इसके विरुद्ध किया गया आचरण अनैतिक है। इस पर समय तथा स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हत्या करना पाप है, तो वह प्रत्येक परिस्थिति में पाप ही होगा।

2. नैतिकता के इस अर्थ की पर्याप्त आलोचना की जाती है। इसे आदर्शवादी तथा अव्यावहारिक बताया जाता है। कुछ लेखकों का कहना है कि नैतिकता का केवल एक ही मापदण्ड नहीं होता। इतिहास एवं अनुभव के आधार पर इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। एक व्यक्ति के लिए शत्रु को मार कर खा जाना एक अनैतिक कार्य है, किन्तु वह यह सिद्ध नहीं कर सकता कि उसके मूल्य उस जगह के व्यक्ति के मूल्य से किस प्रकार उच्चतर हैं जो शत्रु तो क्या मित्र को भी मार कर खा जाता है। इन विचारकों की मान्यता है कि कार्य एवं स्थिति के अनुसार व्यक्ति के नैतिक आचरण का रूप भी परिवर्तित होता रहता है। यदि एक लसपति व्यक्ति चोरी नहीं करता तो हम उसको एक महान् नैतिक व्यक्ति नहीं मान सकते। असल में उसकी नैतिकता उस व्यक्ति से भी नीची है जो अपने बच्चों की भूल मिटाने के लिए चोरी कर लेता है।

अन्तर्राष्ट्रीय आचार-संहिता जैसी कोई चीज है भी अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विचारकों में मतभेद हैं। प्रत्येक देश अपने इतिहास, अनुभव एवं परम्पराओं के आधार पर स्वयं के नैतिक मापदण्ड निर्धारित करता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। इस प्रकार आचरण का कोई अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्ड होने की अपेक्षा प्रत्येक देश की विशेष आचरण-संहिता है।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक आचरण-संहिता के अस्तित्व से सम्बन्धित समस्या का समाधान अनेक रूपों में किया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय धर्म में कोई नैतिक आचरण की संहिता नहीं होती। दूसरे लोग बहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए भी नैतिक मापदण्ड होता है। किन्तु यह मापदण्ड क्या है, उसके बारे में वे एकमत नहीं। कुछ का कहना है कि यह व्यक्तिगत आचरण-संहिता जैसी ही होती है। अन्य विचारकों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के नैतिक मापदण्ड एक विशेष प्रकार के होते हैं।

नैतिक मापदण्ड के अस्तित्व की भाँति इस प्रश्न पर भी विचारकों में पर्याप्त मतभेद है—क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार अनैतिक होता है? जो लोग अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्ड के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, उनके मतानुसार यह प्रश्न अप्रासंगिक है। दूसरों के लिए यह प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है। इस सम्बन्ध में एक सामाजिक धारणा यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता और कानून का जितना पालन किया जाता है उससे अधिक उसका उत्पन्न किया जाता है।

कुछ विचारक यह मानते हैं कि अधिकांश व्यक्ति प्रायः अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन नैतिक मापदण्डों का पालन करते हैं जिनका कि वे उपदेश देते हैं। कुछ नैतिक आचरण ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में अपना लेता है, किन्तु अपराधपूर्ण परिस्थितियों में वह उनका पालन नहीं कर सकता और इस उत्पन्न को विवेकपूर्ण एवं न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत के अनुसार आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती। कुछ परिस्थितियों में राजनीतिज्ञ आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करते हैं तथा उन्हें अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध भी निर्णय लेने पड़ते हैं क्योंकि उनके सामने कोई विकल्प नहीं होता।

नैतिकता के इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए अन्य विचारक यह मत व्यक्त करते हैं कि नैतिक आचरण और सुगमता का मेल नहीं है। आवश्यकता और मजबूरी यदि हमको नैतिकता के विरुद्ध कर देती है तो यह हमारी स्वयं की कमजोरी की प्रतीक है। आर्नोल्ड वॉल्फर्स (Arnold Wolfers) के बयानानुसार, "यदि एक राजनीतिज्ञ यह निर्णय लेता है कि उसके देश की सुरक्षा के लिए खतरा इतना महान् है कि उसका युद्ध में उलझना आवश्यक हो गया है तो यहाँ वह राष्ट्रीय सुरक्षा की अत्यधिक मूल्य प्रदान कर रहा है।" कहने का अर्थ यह है कि कई बार मूल्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और उस समय प्राथमिकता के आधार पर वह चुनना होता है कि किस मूल्य को महत्व दिया जाए। कुछ मूल्यों की साधना में रहने पर युद्ध आवश्यक हो सकता है किन्तु तब निर्णायक को यह तय करना होगा कि क्या वे मूल्य इतने उच्च हैं कि उनके लिए अन्य मूल्यों को बलिदान किया जा सकता है। इस प्रकार आवश्यकता एवं मजबूरी का नाम लेना तो केवल बहाना मात्र है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कार्य पूर्ण शुभ या अशुभ नहीं होता, वरन् प्रत्येक कार्य में अच्छाई व बुराई दोनों तत्त्व पाए जाते हैं और तब यह तय करना कि कम बुराई क्या है उसी को अपनाया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का प्रश्न अत्यन्त जटिल है। अधिकांश व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए दूसरों की हत्या कर देना उचित मानते हैं। उनके मतानुसार न्यायपूर्ण युद्धों में जो हत्याएँ होती हैं वे उचित तथा नैतिक हैं। एक देश जिस समय युद्ध कर रहा होता है उस समय उसका कोई भी नागरिक यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसका देश अन्धायपूर्ण युद्ध में सलग्न है। प्रायः सभी व्यक्ति इस बात में विश्वास करते हैं कि अपराधी को उसके दुष्टर्मों के लिए दण्ड दिया जाना चाहिए और गम्भीर अपराध के लिए व्यक्ति की जान भी ले ली जाए तो बुरा नहीं है। यह कार्य भी न्यायपूर्ण एवं नैतिक ही माना जाएगा, किन्तु यह व्यवहार इन बयानों के विपरीत पड़ता है कि 'अपने शत्रु को प्यार करो', 'बुराई का बदला बुराई से न दो', आदि। नैतिकता के समर्थकों का कहना तो यह है कि "भला करने वाले भलाई लिए जा, बुराई के बदले दुष्टाएँ दिए जा।" नैतिकता का यह रूप आदर्श है, किन्तु केवल व्यक्तिगत जीवन में ही इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिकता को राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता। यहाँ विदेश-नीति के निर्णायकों के हाथ में असंख्य लोगों का जीवन होना है और अपने व्यक्तिगत मूल्यों की खातिर उन्हें इसकी बाजी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कभी-कभी अन्धाय का विरोध करने के लिए हिंसात्मक साधनों को अपनाना जरूरी हो जाता है। जो लोग यथास्थिति से सन्तुष्ट हैं वे यह कहते हैं कि यथास्थिति को बदलना और इसके लिए शक्ति का प्रयोग करना अन्धाय है, किन्तु यही लोग उस यथास्थिति को कायम रखने के लिए शक्ति के प्रयोग को न्यायोचित् मानते हैं।

निहित दबाव के कारण विभिन्न देश अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता मानने के लिए बाध्य होते हैं। आन्तरिक दबावों में निर्णायकों की स्वयं की अन्तरात्मा एवं देशी लोकमत की गणना की जा सकती है। वैसे लोगों की प्रायः यह प्रवृत्ति रहती है कि वे अपनी सरकार की अपेक्षा दूसरे देशों की सरकार को भला-बुरा कहते हैं, किन्तु उनके स्वयं के देश की सरकार भी उनकी आलोचना से बच नहीं पाती। संयुक्तराज्य अमेरिका में वियतनाम युद्ध एवं बमबारी के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए तथा जुलूस निकाले गए वे इसी बात के प्रमाण हैं। यह कहा जाना है कि सन् 1961 में क्यूबा के विरुद्ध अमेरिकी शक्ति के प्रयोग करने पर देश में भारी विरोध होने की प्राणवाधी और दमोलीत वह प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त नहीं की गई।

जनमत की आलोचना एवं विरोध का भय होने के कारण ही आज के देश केवल सुरक्षात्मक एवं न्यायपूर्ण युद्ध ही लड़ना चाहते हैं। इसके अनिश्चित अनेक कारणों से आज विश्व के अधिकांश देश स्थायी विश्व-व्यवस्था चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने दीर्घवालीन लक्ष्य को ध्यान में रखकर कुछ छोटी-मोटी इच्छाओं की अभिव्यक्ति की अपेक्षा कर सकते हैं।

विदेश-नीति के निर्णायकों पर विश्व जनमत का प्रभाव भी उल्लेखनीय रूप में पड़ता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश गंवार के गामने अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप रचना चाहता है। साथ ही वह अपने प्रत्येक कार्य को न्यायोचित् ठहराने के लिए

प्रचार-साधनों का आश्रय लेता है। जिन लोगों का यह विश्वास है कि केवल शक्ति ही सब कुछ होती है, वे भी इस तथ्य को अग्राह्य रखते हैं। प्रत्येक राज्य की सामर्थ्य उसकी शक्ति एवं सहमति (Consent) पर निर्भर करती है। उसे जितनी अधिक सहमति प्राप्त होती है उसे शक्ति की उतनी ही कम जरूरत होती है।

मनोबल (The Morale)

अंग्रेजी शब्द Morale का हिन्दी रूपान्तर मानसिक या नैतिक अवस्था के रूप में किया जाता है। व्यवहार में इसको 'मनोबल' शब्द द्वारा भी व्यक्त किया जाता है जो अन्य शब्दों में अधिक उपयुक्त है।

मनोबल का अर्थ

(Meaning of the term Morale)

मनोबल की परिभाषा देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसिद्ध विचारक मॉर्गेन्थो ने बताया था कि राष्ट्रीय मनोबल निश्चय (Determination) का वह अनुपात (Degree) है जिसके अनुसार एक राष्ट्र शान्ति एवं युद्ध के समय अपनी सरकार की विदेश-नीति का समर्थन करता है। मनोबल में राष्ट्र की सारी नियाएँ—औद्योगिक व कृषि-उत्पादन तथा सैनिक तैयारियाँ व कूटनीतिक सेवाएँ समाहित होती हैं। लोकमत के रूप में राष्ट्रीय मनोबल सरकार की विदेश-नीति को इतना प्रभावित करता है कि कभी-कभी तो यदि दोनों के बीच मतभेद पैदा हो जाय तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है अथवा सरकार को अपनी नीति लोकमत के अनुकूल परिवर्तित करनी पड़ती है। प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में मनोबल या लोकमत का प्रभाव स्पष्ट एवं वास्तविक रूप से उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करता है जबकि तानाशाही या राजतन्त्रात्मक राज्यों में ऐसा सम्भव नहीं हो पाता। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन राज्यों में मनोबल या लोकमत का कोई महत्त्व नहीं होता। हिटलर की विदेश-नीति को जर्मनी की जनता के 90 प्रतिशत से भी अधिक का समर्थन प्राप्त था।

यह कहा जाता है कि युद्ध केवल सेनाओं को रणक्षेत्र में भेजने से नहीं जीते जा सकते। जब तक जनता का पूरा सहयोग एवं हार्दिक सहभागिताएँ अपने वीर सिपाहियों का उत्साह-वर्धन न करेंगी, तब तक वे अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ सकते। वे अपनी कुर्बानी को गालूभूमि की सेवा में बलिदान न मानकर आत्म-हत्या समझने लगेंगे। इस प्रकार जनता का मनोबल किसी भी युद्ध की सत्रियता, उत्साह एवं सफलता के लिए एक आवश्यक तत्त्व होता है।

मनोबल कभी-कभी युद्ध के प्रतिरोध (Deterrent) के रूप में भी काम करता है अर्थात् जिस देश के लोगों में एकता होती है तथा वहाँ की सरकार की नीतियों के पीछे जनता का रुल रहता है उस देश पर कोई भी शत्रु-देश आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता; यदि करता भी है तो सोच समझ कर। इस प्रसंग में

भारत पर किए गए पाक आक्रमण के कारणों पर यदि गौर किया जाए तो विदित होगा कि पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया उसके प्रमुख कारणों में एक यह भी था कि उसने भारत में विद्यमान अनेक समस्याओं एवं भेदभावों से गलत अनुमान लगा लिया कि यहाँ का मनोबल ऊँचा नहीं है तथा सरकार की नीतियों को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त होना असम्भव है। ऐसी स्थिति में असंगठित भारत शीघ्र ही उसके कदमों पर आ गिरेगा, किन्तु भारतवासियों ने सकट के समय जो अद्वितीय एकता दिखाई वह आश्चर्यजनक थी। सभी विरोधी दलों ने सरकार की नीतियों को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। सकट का मुकाबला करने के लिए सभी मतभेदों को भुला दिया गया। समय-समय पर सरकारी प्रवक्ताओं एवं विदेशी पत्रों ने यह स्वीकार किया कि भारत का मनोबल बहुत ऊँचा है। इस दृष्टि से गृह मन्त्री नन्दा तो पाकिस्तानी आक्रमण को एक परीक्षा की घड़ी कहकर यह मानने लगे थे कि इस सकट को पार कर भारत वैसा ही होगा जैसा कि आग से तपा हुआ सोना, उसमें कुन्दन जैसी ही चमक आ जाएगी।

पामर तथा पकिस ने मनोबल (Morale) को परिभाषित करते हुए इसे आत्मा का एक तत्त्व माना है जो स्वाभिक्ति, साहस तथा विश्वास से मिलकर बनता है। यह व्यक्तित्व एवं सम्मान की रक्षा की लालसा है, ज्ञात के प्रति 'भावना' है तथा अज्ञात के प्रति भय एवं अरुचि है। यह आत्म-स्वार्थ है। यह आत्म-स्वार्थ इस अर्थ में है कि एक देश का स्वस्थ मनोबल (Healthy Frame of Mind) उस देश के निवासियों में 'समात्मभाव' की स्थापना करता है। इसके अस्तित्व में वह समाज प्रेम, सेवा, बलिदान बन्धुत्व, दाम्पत्य, सत्य, वात्सल्य, भक्ति आदि के भावों से परिपूर्ण हो जाता है। स्थूल जगत् में इन दो भावों के अनेक परिणाम परिलक्षित होते हैं। जब लोग सबके सुख में अपना सुख और सबके दुःख में अपना दुःख देखने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उस देश की विकास-योजनाओं की गति तीव्र हो जाती है। सभी लोग मिल कर सच्चे दिल से परिश्रम करते हैं, राष्ट्रीय हित के प्रागे वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान कर देते हैं। इस सबका परिणाम यह होता है कि वह देश आर्थिक स्थिति, औद्योगिक उत्पादन, सैनिक तैयारी प्रथम और जिस किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाता है, वही सफलता उसके कदम चूमती है।

मनोबल के निर्माण के साधन

(Means for Maintaining Morale)

किसी भी देश में मनोबल के निर्माण के समय बौन-कौन से तत्त्व प्रभावकारी होते हैं इस सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न मत हैं। कुछ विचारकों के मतानुसार मनोबल विकसित होता है; इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। इन विचारकों की मान्यता है कि कोई सरकार या व्यक्ति विशेष यदि किसी भी कारण देश में मनोबल का निर्माण करना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। पामर तथा पकिस के मतानुसार इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय मनोबल (National Morale) कुछ निश्चित तथा अनेक अनिश्चित तत्वों का उल्लेखपूर्ण समन्वय है।

दूसरी ओर विचारकों का एक अन्य समुदाय है जो उक्त मत के सम्बन्ध में दो आपत्तियाँ उठाता है। प्रथम, उनका कहना है कि यदि यह मान लिया जाए कि मनोबल निर्माण का नहीं बल्कि विकास का परिणाम है तो भी क्या यह उपयुक्त न रहेगा कि इस विकास पर प्रभाव डालने वाले तत्त्वों की खोज की जाए। दूसरे, प्रायः यह देखा जाता है कि युद्ध के समय संकट का मुकाबला करने की दृष्टि से राष्ट्रीय मनोबल एकाएक उठ खड़ा होता है। ऐसी अवस्था में उसे हम विकास का परिणाम न मान कर एक विशेष परिस्थिति की उपज कहेंगे। चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के समय भारत में जिस मनोबल का निर्माण हुआ था वह इतना तरकान हुआ कि उसे विकसित मानना असंगत प्रतीत होता है।

उक्त बौद्धिक मतभेदों में अधिक उलझनों की अपेक्षा यह उपयुक्त होगा कि राष्ट्रीय मनोबल (National Morale) के विकास या निर्माण पर सम्भावित या वास्तविक रूप से प्रभाव डालने वाले तत्त्वों की संक्षिप्त जानकारी की जाए। ये तत्त्व निम्न प्रकार हैं—

1. राष्ट्रीय चरित्र (National Character)—राष्ट्रीय चरित्र का अर्थ उन मूल्यों तथा आदर्शों से है जिन्हें एक देश प्राथमिकता देता है जबकि दूसरे देश उसे नहीं देते। एक देश लोगों का चरित्र अर्थात् उनका रहन-सहन, विचार, भाषा, आदर्श, धर्म, संस्कृति आदि उस देश के मनोबल पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। एक धर्म-प्रधान राष्ट्र के लोगों में युद्ध के विरुद्ध मनोबल तैयार करना दुरूह कार्य है। इसी प्रकार व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित देश के लोग अन्तर्राष्ट्रीय समाज के पक्ष में मनोबल का निर्माण नहीं होने देंगे।

पामर तथा पॅकिस के मत में राष्ट्रीय चरित्र एक देश के मनोबल (Morale) के निर्माण में बहुत कम असर डालता है। वे इतिहास के आधार पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि समय-समय पर एक ही देश में दो विरोधी प्रकृति के मनोबल उभरते देखे गए हैं जो इस बात का प्रमाण है कि उस देश के चरित्र की दोनों में से किसी एक मनोबल के साथ एकरूपता नहीं होगी।

2. संस्कृति (Culture)—संस्कृति एक देश के निवासियों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को प्रभावित करती है। बदलती हुई संस्कृति के लोगों का सोचने एवं अनुभव करने का तरीका भी बदल जाता है। बहुत से विचार एवं व्यवहार जिन्हें प्राचीन-संस्कृति आदर्श मानती है, नवीन संस्कृति उन्हें मूर्खतापूर्ण समझती है तथा नवीन संस्कृति में जो आचार-विचार उपयुक्त माने जाते हैं प्राचीन संस्कृति उनको अमानवीय या अमर्यादित घोषित करती है।

कुछ विचारक यह सोचते हैं कि पुरानी संस्कृति से प्रभावित देश के मनोबल की प्रकृति तथा परिणाम उस देश के मनोबल की प्रकृति एवं परिणामों से भिन्न प्रकार के होंगे जिसमें नवीन संस्कृति का प्रभाव है। किन्तु पामर तथा पॅकिस इस मत को भी नहीं मानते और इतिहास के आधार पर ही दोनों प्रकार के मनोबलों में समानता दर्शाते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि सांस्कृतिक अन्तर एक देश के मनोबल को निश्चित करने के तत्त्व नहीं होते।

3. नेतृत्व (Leadership)—एक राष्ट्र का मनोबल उस देश के महान् पुरुषों के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है। भारत-पाक संघर्ष में आकाशवाणी थोड़े-थोड़े समय के अन्तर पर उन वाक्यों को दोहराती थी जो नेहरू ने कभी संसद् में कहे थे। यह प्रयत्न लाभकारी सिद्ध हुआ क्योंकि जब एक भारतवासी को यह याद दिलाया जाता था कि उसके एक स्वर्गीय नेता ने आजादी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने का आह्वान किया था, तो उसकी नसों का रक्त-प्रवाह उत्तेजित हो जाता था। वह मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने में गौरव का अनुभव करने लगता था। इस प्रकार देश में एक उच्च मनोबल की सृष्टि होती है। पामर तथा पकिंस ने इसी विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि एक नेता जनता में लोकप्रिय हो चुका है तो उसके विचारों का प्रभाव उस देश के मनोबल पर पड़े बिना नहीं रह सकता।

राष्ट्रीय मनोबल पर प्रभाव डालने वाले उपर्युक्त तीनों ही तत्त्वों का स्वरूप 'सम्भावित' है अर्थात् ये तत्त्व प्रभाव डाल भी सकते हैं और नहीं भी। इनके अलावा कुछ अन्य तत्त्व भी हैं जो आवश्यक रूप से मनोबल पर प्रभाव डालते हैं। इनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय दो हैं—सरकार का सक्रिय रूप और अवसर।

4. अच्छी सरकार (A Good Govt.)—एक राष्ट्र में स्वस्थ एवं सुगठित मनोबल का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की सरकार सक्रिय हो, गुणवान हो, तथा प्रजा की इच्छा एवं लोकमत के प्रभाव से संचालित हो। जिस देश की सरकार जनतान्त्रिक तरीके से संचालित होती है वहाँ जनता की महत्वाकांक्षाओं तथा सरकार की नीतियों में एकरूपता पाई जाती है। एक देश के मनोबल का वहाँ की राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि का साधन बनना वहाँ की सरकार के गुणों पर निर्भर करता है। जिन देशों की सरकार अच्छी होती है वहाँ का मनोबल उन देशों की तुलना में ऊँचा होता है जहाँ कि सरकार कमजोर है।

सरकार यदि कमजोर होगी तो उसका कुप्रभाव राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्त्वों जैसे प्राकृतिक स्रोत, भौद्योगिक सामर्थ्य, सैनिक तैयारियाँ आदि पर भी पड़ेगा और वह देश कमजोर हो जाएगा। मॉर्गेंथौ (Morgenthau) महोदय के मतानुसार राष्ट्रीय मनोबल को सुधारने का एकमात्र उपाय यह है कि सरकार के रूप को सुधार दिया जाए।

5. परिस्थिति (Circumstances)—राष्ट्रीय मनोबल के निर्माणक तत्त्वों में यह भी एक प्रमुख तत्त्व है जो प्रभावपूर्ण रूप में कार्य करता है। अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ तथा अवसर आ जाते हैं जो राष्ट्रीय मनोबल की सृष्टि का कारण बन जाते हैं। युद्ध में घटने वाली अनेक घटनाएँ राष्ट्र के मनोबल को उत्तेजित करती हैं। सितम्बर, 1965 में जब भारतीय सेनाएँ लगातार युद्ध विराम रेखा के उस पार बढ़ती जा रही थी, भारतीय जनता में जोश की एक लहर घाई हुई थी। प्रत्येक रेडियो के चारों ओर एक मेल-सा लग जाता था तथा प्रत्येक सबर

के साथ जनता की करतल ध्वनि के नीचे रेडियो की आवाज भी दब जाती थी। लोगों में एक अपूर्व उल्लास था। दुश्मन के खड्डो हुए पैरों को देखते में वे इतने लगे गए कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि उनकी स्वयं की कितनी क्षति हो रही है। राष्ट्र का मनोबल युद्ध की इन विजयों के कारण इतना बढ़ गया था कि कई मोर से पूरे लाहौर पर अधिकार करने की या पाकिस्तान को दुनिया के नक्के से हटाने की बातें की जाती थी। सन् 1971 के युद्ध में तो भारतीय सेना का मनोबल अपूर्व सिद्ध हुआ जबकि पाक फौजों का मनोबल इतना टूट गया कि युद्धों के इतिहास में एक बहुत बड़े आत्म-समर्पण का कर्त्तक पाक सैनिक नेतृत्व को भेलना पड़ा। मनोबल परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होना है। माँगैन्वी ने इनी श्रम में कहा था कि यह सब भवतरो पर ही निर्भर करता है।

अक्सर राष्ट्रीय मनोबल को गिरा भी सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि लड़ाई में हार हो जाए, कोई बड़ा नेता मर जाए, जहाज डूब जाए, कोई मित्र धोखा दे जाए, शत्रु की शक्ति बढ़ जाए अथवा देश में ही फसल मारी जाए, हड़ताल हो जाए, बाढ़ आ जाए, रैल दुर्घटनाएँ हो जाएँ, बीमारी फैल जाए तो देश का मनोबल गिर सकता है। कभी-कभी जीत की खबर भी लोगों के उत्साह एवं प्रयासों को ढीला कर देती है।

राष्ट्रीय मनोबल (National Morale) को एक देश की रीढ़ कहा जा सकता है जिसके टूटते ही राष्ट्र का सारा ढाँचा धराशायी हो जाता है। एक देश का गिरा हुआ मनोबल उठाना उतना ही कठिन तथा समय साध्य है जितना टूटी रीढ़ को पुनः कार्यक्षम बनाने का प्रयास। माँगैन्वी ने राष्ट्रीय मनोबल को राष्ट्रीय शक्ति का एक अभिन्न अंग माना है जिसके बिना राष्ट्र की शक्ति एक निर्जीव शक्ति बन कर रह जाएगी। यह केवल घाशा बनकर रह जाएगी जिसे कभी भी वास्तविक नहीं बनाया जा सकता।

नेतृत्व (The Leadership)

राष्ट्रीय शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्त्व नेतृत्व है। राज्य चाहे प्रजातन्त्रात्मक हो या राजतन्त्रात्मक, केवल कुछ लोगों द्वारा ही संचालित किया जाता है। स्विट्जरलैण्ड को अपवाद मान लेने के बाद विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं रह जाता है जहाँ की सरकार के कार्य अथवा विदेश-नीति के मामलों में जनता का हस्तक्षेप हो। देश की बागडोर कुछ नेताओं के हाथों में होती है। इन नेताओं के गुण एवं महानता पर ही उस देश का भविष्य निर्भर करता है। जितने कुशल नेता होंगे तथा जितना प्रभावकारी उनका नेतृत्व होगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली वह देश बन जाएगा।

नेतृत्व के मुख्य रूप से दो कार्य हैं जिनसे वह राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रथम, नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों के बीच समन्वयकी

स्थापना करता है; दूसरे, राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर सके इसके लिए भी नेतृत्व का अस्तित्व आवश्यक होता है। मॉर्गेन्थो (Morgenthau) के शब्दों में सैनिक नेतृत्व के गुण का राष्ट्रीय शक्ति पर बड़ा गहरा असर रहता है। उदाहरण के लिए, 18वीं शताब्दी में प्रशा (Prussia) फ्रेडरिक महान् के नेतृत्व में था। उस समय उसकी शक्ति भी बढ़ी-चढ़ी थी, किन्तु उसकी मृत्यु होते ही प्रशा की शक्ति गिर गई और सन् 1806 में नैपोलियन द्वारा उसकी सेना को हरा दिया गया। इसी प्रकार हम जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं जहाँ बिस्मार्क और हिटलर के नेतृत्व में इतनी राष्ट्रीय शक्ति संचित हो गई थी कि उसने संसार को चकित कर दिया था। सही तथा प्रभावशाली नेतृत्व होने पर एक देश के भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या आदि का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है कि ये सभी तत्त्व उस राष्ट्र को विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र बना सकते हैं। इस प्रकार नेतृत्व का राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों से बड़ा गहरा सम्बन्ध रहता है। नेतृत्व के अभाव में एक देश की सरकार कोई काम नहीं कर सकती, एक विकसित एवं संगठित तकनीक का सदुपयोग नहीं हो सकता; इसके अभाव में मनोबल भी महत्त्वहीन रहता है। नेतृत्व ही वह तत्त्व है जो शक्ति के सम्भावित कारणों को वास्तविक रूप प्रदान करता है। नेतृत्व दूसरे लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, किन्तु दूसरे लोगों के व्यवहार से वह स्वयं अधिक प्रभावित नहीं होता। मैकाइवर और पेज ने नेतृत्व को एक व्यक्ति की ऐसी योग्यता माना था जो उसके पद से सम्बन्धित न होकर उसके स्वयं के व्यक्तित्व से सम्बन्धित होती है। इस योग्यता के आधार पर ही वह लोगों को प्रोत्साहित व निर्देशित करता है। गिब ने नेतृत्व को केवल व्यक्तिगत गुण न मान कर यह स्वीकार किया है कि उस पर सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है।

नेतृत्व के बाल तथा स्यान के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप बदलते रहते हैं। युद्ध के समय किसी दूसरे प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता रहती है जबकि शान्तिबाल में किसी दूसरे ही प्रकार की।

नेतृत्व की विशेषताएँ (Characteristics of Leadership)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व के स्वरूप, महत्त्व एवं उत्तरदायित्वों के उक्त संक्षिप्त परिचय के बाद यह उचित होगा कि उसकी कुछ सामान्य विशेषताओं की भी समझ लिया जाए जिनके कारण एक नेतृत्व को अधिक से अधिक सक्रिय, सफल एवं प्रभावकारी बनने के अवसर प्राप्त होते हैं। ये विशेषताएँ मुख्यतः निम्न हैं—

1. नेतृत्व एक आन्तरिक एवं व्यक्तिगत गुण होता है; यह दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करने तथा उनकी प्रभावित करने का कार्य करता है।

2. नेतृत्व एक चहुँमुखी व्यक्तित्व की माँग करता है। राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक पहलू पर निर्देशन एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता रहनी है। यह मार्गदर्शन किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्ति अपूर्ण है तथा उसकी योग्यता एवं ज्ञान की कुछ सीमाएँ भी होती हैं।

3. उक्त कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि उच्च शिखर पर राजनीतिज्ञों की सहायता के लिए विशेषज्ञ हों और इस प्रकार नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार न होकर विशेषज्ञ के सामान्य निर्देशन के अधीन किया जाए।

इसी भाव को व्यक्त करते हुए पामर तथा पकिरा ने कहा है कि नेतृत्व एक लचीला पद है, इसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जा सकता है किन्तु जिस अर्थ में यह राष्ट्रीय शक्ति का तत्त्व है, इसमें अनेक ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहिए जिनके नेतृत्व के गुणों पर सैनिक सम्भावनाओं का विकास निर्भर करता है।
शान्तिकाल में नेतृत्व (Leadership in Peace-time)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व का सर्वव्यापी महत्त्व है। दो राज्यों के सम्बन्धों को निर्धारित करने वाली इकाइयाँ उन देशों की नेता होती हैं। सामान्य जनता समस्या एवं परिस्थिति को न तो भली प्रकार समझ पाती है और न ही वह इतना समय एवं योग्यता रखती है कि सरकार के निर्णयों को बदल सके। सरकार की कोई भी नीति यदि प्रजा के हितों पर सीधा आघात करती हो तो बात दूसरी है, वरना देश के नेताओं ने जो नीतियाँ अपना ली हैं, प्रजा उनका समर्थन कर देती है।

नेतृत्व का यह उत्तरदायित्व है कि वह दूसरे देशों के साथ आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं अन्य ऐसे सम्बन्ध स्थापित करे जिनके द्वारा उसके देश की राष्ट्रीय शक्ति घटने के बजाय बढ़ती चली जाए तथा राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्त्व परस्पर सहयोग द्वारा शक्ति के उच्चतम शिखर की ओर अग्रसर हों। यह सब करने के लिए नेतृत्व जिस नीति को अपनाता है वह कूटनीति कहलाती है।

जिस प्रकार राष्ट्रीय मनोबल एक देश की आत्मा होता है इसी प्रकार कूटनीति उस देश का मस्तिष्क होती है। इसके अभाव में राष्ट्र के पास चाहे कितने ही अन्य साधन क्यों न हों, वह स्थायी रूप से एक शक्तिशाली देश कभी नहीं बन पाता। कूटनीति (Diplomacy) का मुख्य कार्य, जैसा कि माँगेंथो भी मानते हैं, यह है कि यह विदेश-नीति के साध्य और साधनों को राष्ट्रीय शक्ति के स्रोतों के साथ एकरूप करती है। कूटनीति के माध्यम से उन सभी रास्तों को खोजा जाता है जिनके द्वारा उस राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाया जा सके। कूटनीतिक व्यवहार के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है।

शान्तिकाल में नेतृत्व का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह कूटनीति के माध्यम से दूसरे राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों में वृद्धि करे, अपने आत्म-सम्मान की रक्षा तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का भरसक प्रयास करे।

युद्धकाल में नेतृत्व (Leadership in War-time)

शान्तिकाल में राष्ट्र की शक्ति कूटनीति में रहती है जिसका संचालन नेतृत्व द्वारा किया जाता है। कूटनीति जहाँ असफल हो जाती है वहीं पर युद्ध आरम्भ हो जाते हैं। युद्ध कूटनीति की असफलता का परिणाम है और इस प्रकार यह नेतृत्व

की नीतियों की कुछ अंशों में कमजोरी मानी जाएगी। युद्ध-काल में नेतृत्व को जो उत्तरदायित्व सम्भालने पड़ते हैं वे गुण एवं अनुपात दोनों ही दृष्टियों से शांतिकालीन उत्तरदायित्वों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

पुराने समय में युद्धकालीन नेतृत्व का स्वरूप आज से भिन्न था क्योंकि युद्ध का स्वरूप भी उस समय आज जैसा न था। उदाहरण के लिए हम महाभारत से लेकर सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम तक के भारतीय युद्धों को ले सकते हैं। इनमें सेनाएँ आमने-सामने लड़ती थी, युद्ध की हार-जीत का निर्णय बहुत कुछ योद्धाओं की वीरता, शौर्य, कौशल एवं सेनानायक के नेतृत्व की योग्यता पर निर्भर करता था। सेनापति के गुण और शक्ति को उसकी सेना का गुण एवं शक्ति माना जाता था। कुशल सेनापतित्व, मोर्चाबन्दी, घेराबन्दी आदि द्वारा सेना का नेता विजयश्री का बरण कर लेता था। उस समय के युद्ध सीमित थे; केवल सेनाएँ ही लड़ कर निर्णय कर लेती थी कि कौन शासन करने का अधिकार रखता है।

आज के युद्ध इतने सीमित नहीं बरन् व्यापक प्रकृति के हैं। इसी कारण इनको सर्वांगीण युद्ध (Total War) की संज्ञा प्रदान की जाती है। युद्ध के समय सारा राष्ट्र ही सक्रिय बन जाता है। राज्य के प्रत्येक स्रोत को सुरक्षित व विकसित कर उनको काम में लाने की आवश्यकता पड़ जाती है। देश के नेता का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह राष्ट्र की समस्त सामर्थ्य को तथा उसकी शक्ति के प्रत्येक पहलू को संगठित एवं नियोजित करे। इस प्रकार आज के युद्धों के स्वरूप को देखते हुए नेतृत्व का कार्य केवल यही नहीं है कि वह रणभूमि में जाकर सेना का संचालन करे, अपितु आज उसे रणभूमि से अलग सामान्य नागरिक जीवन में समस्त देश की शक्तियों को सुसंगठित करना होता है।

राज्य चाहे वह प्रजातन्त्रात्मक हो या सर्वाधिकारवादी अथवा राजतन्त्र, राज्य के नेतृत्व की शक्ति कुछ चुने हुए लोगों के हाथों में ही केन्द्रित रहती है। ये चुने हुए लोग ही यह देखते हैं कि देश के सारे साधन युद्ध में देश के पक्ष को शक्तिशाली बनाने में रत हैं अथवा नहीं। पामर तथा पकिस के मतानुसार आज के युद्धों को सर्वांगीण युद्ध (Total War) इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सम्पूर्ण स्रोतों की, सम्पूर्ण संगठन की तथा सम्पूर्ण प्रयत्नों की तथा कभी-कभी सरकार की मारी शक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है। राज्य के राजनीतिक नेताओं का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे राज्य की सारी शक्तियों का समन्वय (Co-ordination) करें।

हंस मॉर्गेन्थौ का कथन है कि युद्ध में सैनिक नेतृत्व में राष्ट्रीय शक्ति पर सदा से ही निर्णायक प्रभाव डाला है।¹ अठारहवीं शताब्दी में प्रशा की शक्ति वास्तव में फ्राँज़िक महान् की सैनिक योग्यता के विलक्षण गुण धार युद्ध सम्बन्धी ब्यूट-रचना के नए दाव-पेचों की भक्त मात्र ही तो थी। फ्राँज़िक महान् की सन् 1786 में मृत्यु तथा सन् 1806 की लड़ाई के बीच के काल में युद्ध-कला में परिवर्तन हो गए थे जिनके

कारण नेपोलियन ने प्रगा की सेना को ध्वस्त कर दिया जो उस समय भी उतनी ही प्रच्छी और सबल थी जितनी कि बीस वर्ष पूर्व। परन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि फ्रैंचिक महान् के पक्ष में लड़ने वाले सैन्य-संचालकों में अपेक्षित सैनिक प्रतिभा का अभाव था जबकि दूसरी ओर अपूर्व सैनिक प्रतिभा का नेतृत्व था और यह नेतृत्व नई व्यूह-रचना तथा नई जागों का युद्ध में प्रयोग कर रहा था। इस तत्त्व ने अन्त में फ्रांस के पक्ष में युद्ध का निर्णय किया। गुनश्च, जबकि युद्ध-तकनीक के विकास के कारण मातायात और परिवहन के साधनों का प्रचुर प्रयोग हो रहा था तब फ्रांस के सेना-संचालक प्रथम महायुद्ध की 'खन्दक में से लड़ने' की तकनीक सोच रहे थे और उधर दूसरी ओर जर्मन जनरल गन्धचालित युद्ध की व्यूहकारी सम्भावनाओं की ओर से पूरी तरह सचेत होकर अपने युद्ध कार्यक्रम को पूर्वापेक्षा कही अधिक और अपूर्व गतिशीलता के साथ आयोजित कर रहे थे। इन दोनों दृष्टिकोणों की टकराहट में केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि पोलैण्ड और सोवियत संघ में भी जर्मनी की श्रेष्ठता 'भांथी के भोके' के रूप में प्रकट हुई जिससे जर्मन शक्ति को लगभग अन्तिम विजय के सन्निकट लाकर खड़ा कर दिया। पोलैण्ड की घुड़सवार सेना पर तथा फ्रांस की स्थिर सेना पर सन् 1934 और 1940 में हिटलर की चरव्यूहभेदी सेनाओं के आक्रमणों और मोतासोर बमवर्षकों के सैनिक तथा राजनीतिक विनाश से, जिसके फलस्वरूप पोलैण्ड की बौद्धिक पराकाष्ठा, सैनिक इतिहास में उसी प्रकार के नए अध्याय का सूत्रपात हुआ जैसा कि सन् 1494 में चार्ल्स अष्टम् के इटली पर आक्रमण के बाद हुआ था। सैनिक नेतृत्व की कुशलता किस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति को उजागर करती है, इसका एक प्रमाण यह है कि द्वितीय महायुद्ध काल में संपुत्तराज्य की उच्च तकनीक और सोवियत संघ की उच्च जनशक्ति ने स्वयं हिटलर के आविष्कारों को अपना कर ही उसका तत्त्वा पलट दिया और उसका नाश कर दिया। अरब-इजरायल युद्धों में भी इजरायल के सैनिक नेतृत्व ने सदैव अरबों को निराश किया। सन् 1973 के युद्ध में पासा कुछ पलटा, लेकिन प्रारम्भिक कुछ दिनों के बाद सैनिक नेतृत्व और सैनिक-गोशल की दृष्टि से इजरायल हावी हो गया। सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध में यह भारतीय सैनिक नेतृत्व ही था जिसने ढाका की लगभग एक लाख पाकिस्तानी फौजों को मय जनरलों के आत्म-समर्पण के लिए मजबूर कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय शक्ति को गौरव प्रदान किया।

स्पष्ट है कि चाहे शान्तिकाल हो या युद्धकाल, चाहे विकास-योजनाओं को निर्धारित करना हो या युद्ध-सामग्री का निर्माण करना हो, प्रत्येक देश को प्रत्येक परिस्थिति में 'नेतृत्व' की आवश्यकता पड़ती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तीव्र-स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रत्येक देश को नेतृत्व के रूप में एक 'श्वशकुमार' की आवश्यकता होती है। 'नेतृत्व' देश को लेकर राष्ट्रीय शक्ति के अन्य स्रोतों के बल पर आगे बढ़ाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि किसी देशरथ द्वारा जाने या अनजाने एक देश के नेतृत्व की हत्या कर दी जाए तो वह देश शक्तिहीन हो जाएगा, उसके शक्ति के सारे स्रोत बिखर जाएँगे तथा अन्धदम्पति की भाँति वह रो-रोकर अपने आप को बिगड़ कर देगा।

अन्त में 'नेतृत्व' पर समाप्ति हम स्टीवेन रोजन और वाल्टर जॉन्स के ओजस्वी शब्दों के साथ करना चाहेंगे।

स्टीवेन रोजन एव वाल्टर जोस (Steven Rosen & Walter Jones) ने नेतृत्व को राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना है। उनके कहने का सारांश यह है कि नेतृत्व वह शक्तिशाली तत्त्व है जो राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों को संगीत देता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य ढंग में परिभाषित करता है और रणनीति के मार्ग का निर्धारण करता है।¹ चीन इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि नेतृत्व मात्र में परिवर्तन के फलस्वरूप एक राष्ट्र की सुप्त शक्तियाँ और क्षमताएँ किस प्रकार गतिमान हो उठती हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रणमंच पर एक दुर्बल अभिनेता किस प्रकार एक ऐसी आत्म-निर्भर शक्ति बन जाता है कि विदेशी मामलों पर उसकी आवाज सुनी जाने लगती है। यह नेतृत्व के गुण पर ही निर्भर है कि समाज जनसंख्या, भू-क्षेत्र और प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न दो देशों में से एक तो दुर्बल, कलहग्रस्त और निष्प्रभावी बना रहता है जबकि दूसरा मजबूत, तेजस्वी और गतिमान बन जाता है। वास्तव में कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी विशेष क्षण में एक ऐसी असाधारण प्रतिभा का उदय होता है जो सुप्त ऐतिहासिक शक्तियों को जगा देती है, घटनाओं के प्रवाह को बदल देती है, एक शान्त और निस्तेज जल-धारा को वेगवती और प्रबल महानदी का रूप दे देती है। नैपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर, डिगॉल, स्टालिन, कास्ट्रो, माओ—ये ऐसी ही करिश्मावादी ऐतिहासिक विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के समीकरण को बदल कर अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास के मार्ग को परिवर्तित कर दिया है। कौन नहीं जानता कि जब ब्रिटेन नाजी भूत के आगे निराश और पस्तहिम्मत हो चला था तब बिस्टन चर्चिल के इन शब्दों ने राष्ट्र में प्राण फूँक दिए थे कि "हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, हवाई क्षेत्रों में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे और गलियों में लड़ेंगे। हम पहाड़ों पर लड़ेंगे, लेकिन हम कभी आत्म-समर्पण नहीं करेंगे।"² यह सच है कि नेतृत्व हवा में शक्ति पैदा नहीं कर सकता, लेकिन यह राष्ट्रीय रचनात्मक शक्ति से उन स्रोतों को जगा सकता है जिन्हें स्पर्श न किया गया हो या जो सोए पड़े हों।³ इतिहास साक्षी

1 "The quality of leadership is the most unpredictable component of national power. Leadership orchestrates the other components, defines goals in a realizable manner, and determines the path of strategy."

—Steven Rosen and Walter Jones : *The Logic of International Relations*, 1974, p. 146.

2 "We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we will never surrender."

—Winston Churchill, Quoted by Rosen and Jones : *Ibid.*, p. 147.

3 'यदि युद्ध एक बार शुरू हो गया तो हम युद्ध विराम मजूर नहीं करेंगे और विश्व युद्ध छिड़ जाने से भी सकोच नहीं करेंगे। यदि समूचा वाकिस्तान भी गूट हो जाए तो कोई बात नहीं, परन्तु हम दुश्मन को अपनी धरती पर पैर नहीं रखने देंगे।'—हिन्दुस्तान, दिनांक 23-3-75

है कि कभी-कभी अकेले एक राजनीतिज्ञ ने निस्तेज प्रवाह को उलट दिया है, एक ऐसा अन्तर पैदा कर दिया है जो राष्ट्र को एक शक्ति के रूप में बदलने वाला हो। क्या यह थोड़ा बहुत-कुछ नेतृत्व को नहीं जाता कि जिस भारत की तस्वीर सन् 1962 के चीनी आक्रमण के बाद अन्तर्राष्ट्रीय चित्रपट पर धुँधली हो चली थी आज उसी भारत के लिए एक 'महाशक्ति' की संज्ञा दी जाने लगी है; जो भारत अमेरिकी दोनों का मोहताज था वही भारत राष्ट्रीय अभिमान से सिर ऊँचा उठाए हुए भीषण कठिनाइयों से सघन करते हुए भी एक अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। नेहरू के बाद नेतृत्व की एक कलक क्रमशः लालबहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई एवं श्रीमती इन्दिरा गाँधी में देखने को मिलती है जो कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उभर कर आए, स्वतः स्पष्ट तथ्य है। अयोग्य और निष्प्रभावी नेतृत्व एक शक्तिशाली राष्ट्र को भी गिरा देता है जबकि योग्य और तेजस्वी नेतृत्व एक निर्बल राष्ट्र को सबल राष्ट्र में बदल देता है।

राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन (Evaluation of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण तत्वों-भूगोल, प्राकृतिक साधन, जनसंख्या, प्राविधिक ज्ञान, विचारधारा, मनोबल, नेतृत्व आदि का विवेचन किया जा चुका है। ये सभी तत्व परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और मिलकर राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि करते हैं। यह अलग बात है कि किसी एक अथवा दो तत्वों का अन्य तत्वों के मुकाबले अधिक योग हो। स्टीवेन रोजन एवं वाल्टर जोस (Steven Rosen and Walter Jones) ने लिखा है कि "सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं, तथापि औद्योगिक क्षमता एक असाधारण आर्थिक चल (Economic Variable) है और नेतृत्व का गुण सबसे प्रमुख राजनीतिक तत्व (Political Factor) है।"¹ लेखक द्वय ने आगे लिखा है कि प्रत्येक राज्य में कुछ न कुछ ऐसी क्षमता (Capacity) होती है जिसके प्रभाव से वह इस विश्व के रंगमंच पर प्रभाव डालता है और नेतृत्व उन सीमाओं तथा उद्देश्यों का निर्धारण करता है जिनके लिए इस क्षमता (Capacity) का प्रयोग किया जाना है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनना है तो उसे औद्योगिक क्षमता और योग्य नेतृत्व से सम्पन्न होना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों के संरक्षण, सम्बर्द्धन और विकास की उपेक्षा कर देगा। सभी तत्वों का समन्वित समन्वय न केवल उपयोगी है बल्कि राष्ट्रीय शक्ति की प्रभावोत्पादकता के लिए आवश्यक है। अल्पविकसित और बिकसित राष्ट्रों की परिस्थितियाँ और आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं। उनके अनुसार ही राष्ट्र विशेष को शक्ति-तत्वों की प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी। उदाहरणार्थ, एक अल्पविकसित राष्ट्र केवल औद्योगिक

क्षमता के विकास में जुट जाता है और अन्य आर्थिक कारकों की उपेक्षा कर देता है तो असन्तुलित अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों पर विपरीत प्रभाव डालेगी। इसी तरह युद्ध अथवा सैनिक क्षमता के विकास की जगह आर्थिक क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता देना अल्पविकसित राष्ट्र के लिए अधिक आवश्यक है।

शक्ति का प्रयोग (Exercise of Power) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में अनेक रूप धारण करता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक पारितोषिक और दण्ड के माध्यम से दूसरे देशों पर प्रभाव डाला जाता है, विभिन्न उपायों से (जैसे विद्याभियों के आदान-प्रदान से, प्रकाशित सामग्री से) सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार किया जाता है, प्रत्यक्ष प्रचार-प्रयत्नों द्वारा (जैसे वायस ऑफ अमेरिका प्रोग्राम द्वारा) दूसरे देशों में जनमत को प्रभावित किया जाता है, और इसी तरह शस्त्रास्त्रों की अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री द्वारा दूसरे राष्ट्रों पर प्रभाव डाला जाता है। संयुक्तराज्य अमेरिका किसी राष्ट्र को शस्त्रास्त्र-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर तो किसी राष्ट्र को भारी मात्रा में हथियार बेचकर या उपहार में देकर अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए दबावकारी नीति अपनाना रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और सन्धि-गुटों के भीतर भी सोदेबाजी तथा लाविङ्ग के रूप में शक्ति-प्रसार के प्रयत्न किए जाते रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न साधनों द्वारा प्रभाव का विस्तार किया जाता है, कभी-कभी सैनिक बल-प्रयोग द्वारा भी। वस्तुतः, सैनिक शक्ति का प्रयोग आज के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बन गया है। अरब राज्य कूटनीतिक दबाव, प्रचार, आर्थिक प्रबन्धों आदि के माध्यम से इजरायल के साथ अपनी सीमाओं में सशोधन का प्रयत्न कर सकते हैं लेकिन प्रादेशिक सघर्षों में बहुधा युद्ध ही अन्तिम साधन (The ultimate means) माना जाता है।

राष्ट्रीय शक्ति एक 'समग्र वस्तु' है जिसके निर्माण में सभी तत्व एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए अपना योग देते हैं। जब कभी शक्ति की दृष्टि से हम एक राष्ट्र का स्तर मापें तो यह अपेक्षित है कि हम अप्रभावित महत्त्वपूर्ण बातों को अवश्य ध्यान में रखें—

1. समन्वयात्मकता—राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों के बीच अन्धे और लगड़े का सा सम्बन्ध है अर्थात् यदि ये तत्व परस्पर मिलकर समन्वित रूप से कार्य करते हैं तो अवश्य ही एक राष्ट्र की शक्ति में अभिवृद्धि होती है। पर यदि ये अलग-अलग रहें, हर तत्व अपनी-अपनी खिचड़ी अलग पकायें तो न केवल इनसे राष्ट्र कमजोर होगा बल्कि इनका महत्त्व भी खो जाएगा। पामर एव पकिंस ने अपने विख्यात ग्रन्थ 'इटरनेशनल रिलेशंस' में राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों पर एक-एक करके विचार किया है और बनाने का प्रयत्न किया है कि परस्पर सम्बन्धित न रहने पर वे नष्ट हो जाएंगे अथवा प्रभावहीन रहेंगे।

2. सापेक्षता—शक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होती और किसी भी राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन सापेक्ष (Relative) होना चाहिए। जब कभी हम एक राष्ट्र को शक्तिशाली कहते हैं तो हमारे अस्तित्व में दूसरे ऐसे राष्ट्रों का बिना होना है जिन्हें

हम उस राष्ट्र की तुलना में कमजोर मानते हैं। पामर एवं पकिंस ने इस तर्क को बड़े रोचक और युक्तिपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि एक लक्षपति व्यक्ति करोड़पतियों के समूह में घनवान नहीं कहा जाएगा, एक चालीस वर्षीय व्यक्ति दस वर्ष के बालक की तुलना में वृद्ध माना जाएगा, लेकिन अस्सी वर्षीय व्यक्ति के समक्ष वह युवक समझा जाएगा। पचास डिवीजन सेना, तीन सौ युद्धपोन और दो हजार बमबर्कों वाला राष्ट्र शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन जो राष्ट्र इससे भी अधिक सैनिक शक्ति और साधनों से सम्पन्न है उसके समक्ष वह शक्तिशाली नहीं माना जाएगा।¹ अभिप्राय यह है कि राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए तुलनात्मक रूप में दूसरे राष्ट्रों की शक्ति को भी कसोटी पर कसना पड़ेगा।

3 परिवर्तनशीलता—राष्ट्रीय शक्ति एक गतिशील वस्तु है और उसके विभिन्न तत्त्वों की स्थिति समयानुसार बदलती रहती है। यदि कल कोई देश सर्वोच्च शक्ति था तो आवश्यक नहीं है कि आज या आने वाले समय में भी वह अपनी उसी स्थिति को बनाए रख सकेगा। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के परिणाम राष्ट्रीय शक्ति के उत्थान और पतन, राष्ट्रों के प्रभुत्व में कमी और अभिवृद्धि के जीते-जागते प्रमाण हैं। वास्तव में प्रत्येक देश का भविष्य बहुत कुछ इन तीन विकल्पों पर आधारित होता है—(क) देश की शक्ति दृढ़नी ही बनी रहेगी, (ख) देश की शक्ति का ह्रास हो जाएगा, एवं (ग) देश की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। राष्ट्रों की शक्ति-स्थिति में इस परिवर्तन के सम्भावित कारणों को व्यक्त करते हुए पामर एवं पकिंस ने लिखा है—“एक राज्य की सेनाओं के आकार में वृद्धि अथवा कटौती हो सकती है, उसका मनोबल गिर अथवा उठ सकता है, नेतृत्व बदल सकता है, कच्चे माल का अभाव या बाहुल्य हो सकता है, प्राविधिक प्रक्रिया में सुधार आ सकता है, युद्ध में प्रयुक्त होने वाले नवीन हथियारों का आविष्कार हो सकता है, महामारी बाढ़ और भूचाल से उत्पादन में गिरावट आ सकती है और श्रमिकों का नाश हो सकता है तथा मनोबल गिर या टूट सकता है, सन्धियाँ की ओर तोड़ी जा सकती हैं—ये सभी अवस्थाएँ राष्ट्रीय शक्ति के एक अथवा अनेक तत्त्वों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं और इस प्रकार किसी भी राष्ट्र की शक्ति-स्थिति में परिवर्तन का कारण बन सकती हैं।”

उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में यह अपेक्षित है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति के विषय में कोई निर्णय लेते समय हम रचनात्मक कल्पना को काम में लें, इतिहास की परिवर्तनशील घटनाओं को ध्यान में रखें, इतिहास द्वारा परिचित परिस्थितियों के साथ समायोजन के लिए तैयार रहे और वर्तमान में जो हो रहा है तथा भविष्य में जो हो सकता है इनके बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रस्तुत रहे। भविष्य को सुनिश्चित की अपेक्षा सम्भावित मानकर आगे बढ़ें।

मॉर्गन्थो के विचार

मॉर्गन्थो ने एक राष्ट्र द्वारा अपनी शक्ति के मूल्यांकन के सुन्दर में तीन विशेष भूलों (Typical Errors) की ओर संकेत किया है—

प्रथम भूल यह है जब एक राष्ट्र स्वयं एल निरंकुश शक्ति बन बैठता है और दूसरी शक्तियों के सापेक्ष महत्त्व की अवहेलना करता है।

दूसरी भूल यह है जब कोई राष्ट्र अतीतकाल में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले अपने किसी एक शक्ति-तत्त्व को ही स्थायी मान बैठती है और उस परिवर्तन की उपेक्षा करता है जो अधिकांश शक्ति-तत्त्वों को शासित करता है।

तीसरी भूल तब होती है जब कोई राष्ट्र अपने किसी एक ही शक्ति-तत्त्व को निर्णायक महत्त्व देता है और अन्य शक्ति-तत्त्वों की परवाह नहीं करता।

दूसरे शब्दों में मॉर्गेन्थो के अनुसार, “प्रथम भूल एक राष्ट्र की शक्तियों का अन्य राष्ट्रों की शक्तियों के साथ सामञ्जस्य स्थापित न करने में निहित है, दूसरी भूल एक समय की वास्तविक शक्ति का भविष्य की सम्भाव्य शक्ति से सामञ्जस्य स्थापित न करने में और तीसरी भूल एक ही राष्ट्र के एक शक्ति-तत्त्व का उसी राष्ट्र के अन्य तत्त्वों के साथ सामञ्जस्य स्थापित न करने में निहित है।”

मॉर्गेन्थो ने एक तत्त्व को प्रधानता देकर और उसी के आधार पर किसी राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन करने की आधुनिक प्रवृत्ति की जोरदार आलोचना की है। उनका निश्चित मत है कि एक तत्त्व के आधार पर किसी राष्ट्र की शक्ति के सम्बन्ध में निकाले गए निष्कर्ष केवल प्रांशिक रूप से ही सत्य हो सकते हैं। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने भू-राजनीति, राष्ट्रवाद तथा सैनिकवाद नामक तीन विचारधाराओं के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो केवल एक ही तत्त्व को प्रधान मान कर आगे बढ़ती हैं—भू-राजनीति (Geo-politics) की विचारधारा के समर्थक मेकाइडर का कहना था कि पूर्वी यूरोप पर शासन करने वाली शक्ति को यूरोप और एशिया पर नियन्त्रण स्वाभाविक है और यूरोप तथा एशिया पर नियन्त्रण रखने वाला विश्व का स्वामी बन जाएगा। राष्ट्रवाद (Nationalism) की विचारधारा जाति, रक्त, धर्म आदि पर आधारित एकता को प्रधान मानकर चलती है और सैनिकवादी (Militarism) विचारधारा यह मानकर चलती है कि जिस देश के पास जल, धल तथा वायु सेना की सख्या अधिक है, वही देश शक्तिशाली होगा। ये तीनों ही विचारधाराएँ एक पक्षीय हैं जो हमें पूर्ण सत्य से ओझल रखती हैं। अतः अत्यावश्यक है कि किसी एक तथ्य के आधार पर राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन न किया जाए।

मुख्य शक्तियाँ—सैनिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से और कुल राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से

(Major Powers—From Military, Population and G. N. P. Point of View)

यदि भिन्न-भिन्न तत्त्वों की दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों को प्रमुखता दें तो हम कुछ इस प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं जैसे प्रमुख सैनिक शक्तियाँ, जनसंख्या के आधार की दृष्टि से बड़े देश, कुल राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख शक्तियाँ, आदि। स्टीवेन रोजन एव वाल्टर जोन्स ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों के विवेचन में सैन्य-बल, जनसंख्या, एव कुल राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से विश्व की प्रमुख शक्तियों (प्रमुख राष्ट्रों) का उल्लेख किया है। यद्यपि जो सूचियाँ दी गई हैं वे मन् 1968 के वर्ष से सम्बन्धित हैं, लेकिन हमारे सामने महत्वपूर्ण तुलनात्मक आधार प्रस्तुत करती

हैं और सूचीबद्ध राष्ट्रों की स्थिति में अभी तक ऐसा कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं आया है कि जो राष्ट्र सैनिक दृष्टि से 1968 में नम्बर 3 या 4 था वह 1975 में नम्बर 1 या 2 बन गया हो या जो राष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से 1968 में नम्बर 3, 4 या 5 पर हो वह नम्बर 1 या 2 पर आ गया हो। रोजन एवं जोन्स द्वारा प्रस्तुत सूचियाँ इस प्रकार हैं¹—

I दस प्रमुख सैनिक शक्तियाँ, 1968
(Ten Major Military Powers, 1968)

देश	सैनिक व्यय (Billion Dollars)	सशस्त्र सेनाएँ (Million Men)	सैनिक व्यय प्रति व्यक्ति (Dollars)
1. संयुक्तराज्य अमेरिका	81	3.5	23,000
2. सोवियत संघ	55	3.5	15,900
3. चीन	8	3.1	2,400
4. फ्रांस	6	0.5	12,100
5. यूनाइटेड किंगडम	6	0.4	13,000
6. पश्चिम जर्मनी	5	0.5	10,900
7. इटली		0.4	5,100
8. पोलैण्ड	2	0.3	6,100
9. कनाडा	2	0.1	17,500
10. भारत	2	1.1	1,400

II .राष्ट्रीय क्रम 1968 में
(National Ranking in 1968)

जनसंख्या की दृष्टि से (By Population)		शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से (By GNP)	
देश	मिलियन	देश	हज़ार मिलियन
1. चीन	800	1. संयुक्तराज्य अमेरिका	866
2. भारत	527	2. सोवियत संघ	413
3. सोवियत संघ	238	3. जापान	142
4. संयुक्तराज्य अमेरिका	201	4. पश्चिमी जर्मनी	133
5. पाकिस्तान	123	5. फ्रांस	127
6. इण्डोनेशिया	114	6. यूनाइटेड किंगडम	103
7. जापान	101	7. चीन	90
8. इराक	80	8. इटली	75
9. पश्चिमी जर्मनी	60	9. भारत	43
10. यूनाइटेड किंगडम	55	10. आर्जील	28
11. नाइजीरिया	54	11. पाकिस्तान	15
12. इटली	53	12. इण्डोनेशिया	11
13. फ्रांस	50	13. नाइजीरिया	6

1 Steven Rosen and Walter Jones : op. cit., pp. 144-145.

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन : कूटनीति, प्रचार और राजनीतिक युद्ध (Instruments for the Promotion of National Interest : Diplomacy, Propaganda and Political Warfare)

“अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के सभी साधनों और तकनीकों का संप्रोपूर्ण सम्बन्धों, शान्ति एवं युद्ध दोनों ही कालों में प्रयोग किया जा सकता है, तथापि इतना अवश्य है कि इनमें से कुछ की प्रकृति अधिकतर सम्झाने-बुझाने की है तो दूसरों की दबावकारी ।” —फ्रैंकेल

यह बताया जा चुका है कि राष्ट्रीय हित और सधर्प अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्त्व हैं और दोनों के बीच सम्बन्धों की महत्ता इस तथ्य से प्रकट होती है कि एक राष्ट्र का हित सदैव दूसरे राष्ट्रों के हित से मेल नहीं खाता और इसलिए राष्ट्रों के बीच परस्पर सधर्प (Conflict) की स्थिति बनी रहती है । इस प्रकार सधर्प का स्रोत राष्ट्रीय हितों के मेल न खाने में है और चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय जगत् से यह स्थिति अर्थात् राष्ट्रीय हितों में मेल न होने की स्थिति कभी समाप्त नहीं हो सकती, अतः स्वाभाविक है कि सधर्प का तत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निरन्तर प्रभावशाली बना रहेगा । सधर्प एवं प्रतियोगिता की स्थिति मुख्यतः इसीलिए कायम रहती है कि प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है और उसके ये प्रयास दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रयासों से टकराते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास बतलाना है कि अपने राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए राज्य प्रायः अनेक साधन अपनाते हैं । अपनी सामर्थ्य और योग्यता तथा भवसर की अनुकूलता, आदि के आधार पर प्रत्येक राज्य यह तय करता है कि उसे इस साधन को किस राज्य के साथ कब अपनाना चाहिए । राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए अपनाए जाने वाले साधनों में प्रमुख ये हैं—

(1) कूटनीति (Diplomacy),

- (2) प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध (Propaganda and Political Warfare),
- (3) राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन (Economic Instruments for National Policy),
- (4) साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद (Imperialism & Colonialism),
- (5) राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध (War as an Instrument for National Policy) ।

प्रस्तुत अध्याय में प्रथम दो साधनों का और अगले अध्यायों में शेष साधनों का विवेचन किया गया है। अपनी विदेश नीति के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य समयानुसार इन साधनों का आश्रय लेता है। कूटनीतिक सम्बन्ध तो सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की विशेषता है जो विशेषतः राष्ट्रीय हित की दृष्टि से प्रचार-कार्य और राजनीतिक युद्ध के कूटनीतिक संचालन में सहायता करते हैं और आर्थिक साधन देश के हितों को सुदृढ़ आधारभूमि प्रदान करने के लिए अपनाए जाते हैं। इन तीनों साधनों का आश्रय तो प्रायः प्रत्येक राष्ट्र हर समय लेता है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तथा युद्ध के साधन ऐसे हैं जो अवसर के अनुसार अपनाए जाते हैं। राष्ट्रीय हितों की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रसारवादी नीतियाँ अपनाता है और साम्राज्य तथा उपनिवेशों की स्थापना करता है। युद्ध का साधन प्रायः बहुत कम अपनाया जाता है। घाज के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण में युद्ध का मार्ग सामान्यतः तभी अपनाया जाता है जब कूटनीति, प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध के साधन अफन हो जाते हैं और राष्ट्र बार्ता द्वारा नहीं यत्निक शक्ति द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का निर्णय ले लेता है। युद्ध के समय भी अन्य साधन सक्रिय रह सकते हैं और प्रायः रहते भी हैं, और इसीलिए युद्ध-विराम हो जाता है। विजय-पराजय द्वारा जब युद्ध का निर्णय होता है तो भी अन्य साधनों द्वारा राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और अधिकाधिक प्राप्ति के दाय-पेच सेले जाते हैं।

राष्ट्रीय-हित का अर्थ

(The Meaning of National Interest)

मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की भाँति राष्ट्रीय जीवन में भी व्यवहार के दो पक्ष होते हैं—पहला, स्वार्थ पक्ष और दूसरा, परमार्थ पक्ष। पहले पक्ष के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक कार्य का प्रभुत्व लक्ष्य उसके स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। इस दृष्टि से एक राष्ट्र का न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी दुश्मन, केवल स्थायी स्वार्थ होते हैं। अन्य देश यदि उस राष्ट्र के स्वार्थ की पूर्ति में सहायक कार्य करेंगे तो अवश्य ही गहरे मित्र बन जाएँगे, किन्तु यह मित्रता केवल तभी तक स्थिर रहेगी जब तक कि इसका आधार 'स्वार्थ-पूर्ति' रहता है। इस आधार के समाप्त होते ही मित्रता का महत्त्व भी समाप्त हो जाता है और यह भी सम्भव है कि वे देश परस्पर उतने ही शत्रु बन जाएँ जितने कि पहले मित्र थे। विश्व का इतिहास एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्रम इस कथन

की पुष्टि के लिए इतने प्रमाण दे सकता है कि यह कथन आज स्वयं सत्य-सा बनता जा रहा है।

राष्ट्रीय क्रियाओं के परार्थमूलक पक्ष में उन सभी कार्यों को समाविष्ट किया जा सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व-शान्ति एवं विश्व-समाज में समानता, स्वतन्त्रता तथा भ्रातृत्व (Liberty, Equality and Fraternity) के सिद्धान्त को सफल बनाने की दिशा में किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से अनेक राष्ट्र पिछड़े देशों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। वे उनके शैक्षणिक, आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान कर वहाँ के जीवन-स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनेक अभिकरण इन परार्थमूलक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (ILO), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण (IAEA), विशेष अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास कोष (SUNFED), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (IDA) तथा बाल-विकास कोष (UNICEF) आदि महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय क्रियाओं के स्वार्थमूलक तथा परार्थमूलक पक्ष का तुलनात्मक महत्व आँकते समय प्रायः स्वार्थमूलक क्रियाओं को ही प्रभावशील ठहराया जाता है। अनेक विचारकों की यह मान्यता बहुत कुछ सत्य है कि परार्थमूलक क्रियाएँ अपने आप में साध्य नहीं हैं, वे साधन हैं तथा उनका अन्तिम लक्ष्य है उस राष्ट्र के स्वार्थों की पूर्ति। उदाहरण के लिए, हम भारत की विदेश-नीति के समर्थकों के तर्कों को ले सकते हैं। यह कहा जाता है कि भारत की शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व पर आधारित गुटनिरपेक्षता की विदेश-नीति को केवल आदर्शवादी मानना भ्रमपूर्ण है क्योंकि देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए विश्व में शान्ति कायम रखना परम आवश्यक है। भारतीय विदेश-नीति विश्व-शान्ति एवं विश्व-सहयोग की अभिवृद्धि का प्रयास करती है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय-हित (National Interest) को उपेक्षणीय या गौण नहीं बनाती बल्कि सच्चे अर्थों में उसकी पूर्ति का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सहयोग एवं सहायता इसलिए देता है कि वह अपने स्वयं के दूरगामी हित में है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक व्यापार के समान है जिसमें कोई भी मर्चा उससे दुगुनी छाप की आशा से किया जाना है। मूल रूप में क्रूर स्वार्थ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों का प्रेरक है। इतिहास हमें इस बात का साक्ष्य है कि राष्ट्रों के बीच जो युद्ध, विवाद, शान्ति, आदि हुईं इन सबके मूल में एक ही कारण था और वह था प्रभावशील राष्ट्रों का अपना-अपना स्वार्थ।

यदि यह मान लिया जाए कि राष्ट्रीय हित ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सब कुछ है तो अब समस्या यह आती है कि आगिर इस 'हित' की प्रकृति एवं स्वरूप क्या है। किन-किन बातों की इस शब्द की परिधि में समाहित किया जाए और किन

धाधार पर ? दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने की समस्या उठ खड़ी होती है। राष्ट्रीय हित कोई स्थिर या शाश्वत वस्तु नहीं है, वह तो एक परिवर्तनशील तत्त्व है जिसे गत्यात्मक (Dynamic Element) कहा गया है। सम्बन्धित इतिहास में एक समय ब्रिटेन का स्वार्थ भारतवर्ष में अपना साम्राज्य कायम रखना था तो दूसरे चरण में उसका यह कार्य हित-साधना की प्रवृत्ति इसका विरोध भी कहा जा सकता है। राष्ट्रीय हित स्थान एवं काल (Time and Place) के परिवर्तन के साथ अपने स्वरूप को बदलता रहता है। एक राष्ट्र के एक ही समय में अनेक हित हो सकते हैं। इन हितों के बीच परस्पर विरोधाभास भी रह सकता है। ऐसी अवस्था में जो हित महत्त्व एवं प्रभाव की दृष्टि से उच्च स्तर का होता है उसको वह राष्ट्र प्राथमिकता प्रदान करता है। निम्न-स्तर वाले राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के कारण अनेक बार राष्ट्रों की राजनीति को असफल होते देखा गया है।

राष्ट्रीय हित (या हितों) के स्वरूप में भिन्नता, अस्थिरता, विरोधाभास, स्तरों की असमानता, आदि अनेक बातें देखने को मिलती हैं। मॉर्गेन्थौ (Morgenthau) के मतानुसार, राष्ट्रीय हित में प्रायः दो तत्त्व निहित होते हैं—एक तो यह कि यह तार्किक रूप से वांछनीय है और इस प्रकार आवश्यक भी। दूसरे, यह स्थिर तथा परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। राष्ट्रीय स्वार्थ को आवश्यक मानने का अर्थ यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकलपता (Identity) की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। इसके अभाव में स्वयं का अस्तित्व भी मिट सकता है। एक देश का राष्ट्रीय हित दूसरे देश के राष्ट्रीय हित के अनुकूल भी हो सकता है और विपरीत भी, किन्तु आज के सम्पूर्ण युद्ध (Total War) के युग में एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए तथा राजनीतिक नैतिकता को स्थिर रखने के लिए वह आवश्यक है कि वह राष्ट्र अपने स्वार्थों को निर्धारित करते समय दूसरे राष्ट्रों के हितों का भी ध्यान रखें तथा दोनों के बीच सामंजस्य की स्थापना का प्रयास करें। राष्ट्रीय हितों की मान्यता यह नहीं होती कि विश्व में सहयोग रहेगा तथा संसार में शान्ति बनी रहेगी और न ही यह होती है कि संसार में संघर्ष एवं युद्ध छिड़ जाएगा वरन् इसका यह विश्वास है कि संसार में हमेशा संघर्ष तथा विवाद बने रहेंगे तथा ये विवाद युद्ध का रूप धारण न कर लें इसके लिए कूटनीति (Diplomacy) के माध्यम से इन संघर्षों के बीच सन्तुलन की स्थापना कर ली जाएगी।

राष्ट्रीय स्वार्थ अथवा राष्ट्रीय हित के उपर्युक्त रूप को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय हित के साधनों को जानना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित (National Interest Defined in Terms of National Power)

राष्ट्रीय हित की प्रकृति एवं स्वरूप सम्बन्धी उपर्युक्त विचारों को मानकर अध्ययन करने से मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय हित की

प्राप्त करने का मुख्य साधन 'शक्ति' है। राष्ट्र हित का चाहे कोई भी स्वरूप एवं लक्ष्य क्यों न हो एक देश उसे तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्ति हो। शक्ति अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, भौगोलिक शक्ति, सैनिक शक्ति, आदि। शक्ति के इन रूपों का वरुण राष्ट्रिय शक्ति के तत्वों का अध्ययन करते समय किया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के गणमान्य विद्वानों के मतानुसार राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित के बीच इतना गहरा एवं अभिन्न सम्बन्ध है कि दोनों को पृथक् करने से दोनों का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इन विचारकों के अनुसार यदि राष्ट्रीय शक्ति को ही राष्ट्रीय हित मान लिया जाए तो प्रतिशयोक्ति नहीं होगी। यह मत सही भी है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र सदैव शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है और शक्ति का संघर्ष ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास का मूल तत्त्व है। 'शक्ति' यद्यपि एक साधन है जिसका प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना, उन्हें सम्भव बनाना तथा राष्ट्र को विश्व-समाज में उच्च स्थान प्रदान करना है, तथापि ये समस्त बातें इतनी प्रचलित चुकी हैं कि आज शक्ति एक साधन मात्र न रह कर साध्य बन गई है। यही कारण है कि अनेक राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने की धुन में अपने अस्तित्व तक को दाव पर लगा देते हैं। हिटलर के जर्मनी और मुसोलिनी के इटली के सदर्भ में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र का सबसे प्रमुख 'राष्ट्रीय हित' (National Interest) है जिसे प्राप्त करने के बाद ही अन्य हितों को प्राप्त करना सम्भव होता है। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्त्व यदि एक देश में सन्तुलित एवं सुविकसित रूप में प्राप्त होते हैं तो स्पष्ट है कि वह देश उन देशों की प्रपेक्षा अधिक शक्तिशाली है जिनके पास इन तत्वों का अभाव है। एक राष्ट्र का यह सबसे बड़ा हित होगा कि राष्ट्रीय शक्ति के इतने तत्वों का सन्तुलित विकास किया जाए और उन सभी बाधाओं को दूर किया जाए जो राष्ट्रीय शक्ति को उच्च शिखर तक पहुँचने में रुकावट डालती है। उदाहरण के लिए यदि हम एक देश की आर्थिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ औद्योगीकरण करना पड़ेगा। जिस देश में औद्योगीकरण (Industrialization) किया जाता है वे देश अविकसित होने के कारण मुख्यतः कृषि-प्रधान होते हैं तथा वे उन सभी दृष्टिकोणों, सामाजिक संगठनों एवं तकनीकों का विरोध करते हैं जिनको एक औद्योगिक समाज की विशेषता माना जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ तीव्र गति से औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता यद्यपि वह उन देश का प्रधान राष्ट्रीय हित होता है। इस हित को प्राप्त करने के लिए जनता में शिक्षा का प्रसार किया जाएगा, यहाँ के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जाएगा तथा साथ ही विकसित राष्ट्रों से उसका सम्पर्क स्थापित किया जाएगा। किन्तु यह सब करने के लिए पूँजी की प्रावश्यकता होती है। बिना पूँजी के एक अर्द्ध विकसित (Semi-developed) देश के नागरिकों को परिवर्तन के लिए पहल करने योग्य बनाना असम्भव है, साथ ही पूँजी का औद्योगीकरण की प्रक्रिया

में भी महत्व है। अतः पूँजी प्राप्त करना उस देश का राष्ट्रीय हित बन जाता है। इसे प्राप्त करने के मुख्य रूप से तीन तरीके हो सकते हैं—

प्रथम, पूँजी दूसरे देशों से सहायता एवं कर्ज के रूप में प्राप्त की जाय;

द्वितीय, पूँजी अपने देश में ही उत्पादन की मात्रा बढ़ा कर प्राप्त की जाए;

और

तृतीय, पूँजी बढ़ाने का तीसरा उपाय निपेधात्मक है अर्थात् देश की खपत (Consumption) को कम कर दिया जाए—जैसा कि खाद्य-स्थिति में स्वावलम्बन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समय का खाना छोड़ने एवं इसी प्रकार के अन्य प्रतिबन्ध लगा कर किया गया था।

जहाँ तक पूँजी को विदेशों से प्राप्त करने का प्रश्न है वह किया जाना चाहिए और उसके बिना प्रगति नहीं की जा सकती, किन्तु साथ ही केवल विदेशी सहायता पर निर्भर रह कर ही एक देश आत्म-सम्मान के साथ अपना समुचित विकास नहीं कर सकता। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि देश की पैदावार को बढ़ाया जाए। साम्यवादी चीन में मानव-शक्ति का अमानवीय रूप से प्रयोग इसी लक्ष्य को लेकर किया गया है। इस प्रकार औद्योगीकरण की प्रक्रिया में एक देश का जीवन-स्तर प्रारम्भ में तो बढ़ने की अपेक्षा घटता है और यह जीवन-स्तर की बसोटी अप्रत्यक्ष रूप से उस देश का राष्ट्रीय हित (National Interest) है।

असल में राष्ट्रीय हित गिरिगिट की तरह रंग बदलता रहता है क्योंकि परिस्थितियाँ एवं समय की आवश्यकताएँ उसे जैसा चाहती है मोड़ देती हैं, किन्तु फिर भी यह एक सार्वभौमिक सत्य (Universal Truth) है कि राष्ट्रीय हित बिना शक्ति के प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करना एक राष्ट्र का ऐसा हित है जो कि सभी कालों में एवं सभी स्थलों में स्थिर रहता है। परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव आते हैं और जाते हैं, किन्तु राष्ट्र की 'राष्ट्रीय शक्ति' में वृद्धि की आकांक्षा अप्रभावित बनी रहती है। अब तक के अनुभवों से ऐसा प्रतीत होता है कि 'राष्ट्रीय शक्ति' के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित (National Interest Defined in Terms of National Power) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सार्वकालिक अपरिवर्तनशील सत्य है और शायद इसी कारण मॉर्गेंथौ (Morgenthau) ने यथार्थवाद के समर्थकों को अपनी विदेश-नीति का निर्धारण करते समय दूसरे देश के 'शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित' को ध्यान में रखने का परामर्श दिया है। राष्ट्रीय हित के स्वरूपों को ध्यान में रखकर यदि अध्ययन किया जाए तो हम एक देश के व्यवहार तथा उसके विशिष्ट दृष्टिकोण के बारे में भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं।

राजनय अथवा कूटनीति

(Diplomacy)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सम्पूर्ण ताना-बाना ही कूटनीतिपूर्ण है। कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों को गतिशीलता एवं एकरूपता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय हितों की प्रगति के लिए शक्ति के जो विभिन्न तत्त्व हैं उन्हें कूटनीति के माध्यम से ही वास्तविक रूप में प्रभावी बनाया जा सकता है। कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है। यदि उसका दृष्टिकोण दूषित है, उनके निर्णय गलत हैं और उसके निश्चय कमजोर हैं तो भौगोलिक स्थिति के तमाम लाभ, साधन पदार्थ व कच्चे माल, औद्योगिक उत्पादन की आत्म-निर्भरता, सैनिक तैयारी, जनसंख्या के गुण व अधिक लाभ, तकनीकी प्रगति आदि विभिन्न बातें अन्त में एक राष्ट्र के लिए कम योगदान दे पाएंगी। वह राष्ट्र, जो इन लाभों भयवा इन तत्त्वों की उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है, अपेक्षित और स्थायी सफलताएँ तभी प्राप्त कर सकेगा जब उसकी कूटनीति उत्तम है। यदि कूटनीति गलत और अविवेकपूर्ण है तो वह अन्य तत्त्वों से प्राप्त लाभों को खो बैठेगा और अपने अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों में क्षीण हो जाएगा।¹

कूटनीति राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विदेश नीति को चाहे जितनी अच्छी तरह योजनाबद्ध किया जाए, उसकी सफलता अन्ततोगत्वा उत्तम कूटनीति पर निर्भर है। सैद्धान्तिक दृष्टि से भारत की विदेश-नीति आदर्श है, उसके तत्त्व यथार्थवादिता के गुण भी लिए हुए हैं, लेकिन अनेक अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्याओं में हम अपने वाञ्छित उद्देश्यों को बहुत कुछ इसीलिए प्राप्त नहीं कर पाए हैं क्योंकि विदेश-नीति को सही कूटनीतिक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। एक सही, सुनियोजित, विवेकपूर्ण और सश्रिय कूटनीति राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि में जितना महत्वपूर्ण योग दे सकती है, उतना अन्य कोई साधन नहीं। कूटनीति के महत्व का उल्लेख करते हुए मॉर्गेंथो ने लिखा है, "ऐसे राष्ट्र को उस राष्ट्र के सम्मुख झुकना पड़ेगा जिसकी कूटनीति अपनी राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्त्वों का सम्पूर्ण प्रयोग करती है और इस प्रकार अपनी स्वयं की उत्तमता से अन्य देशों की कमी की पूर्ति करने में सफल हो जाती है। अपने राष्ट्र की शक्ति-सम्भावनाओं का पूर्ण लाभप्रद प्रयोग करते हुए एक योग्य कूटनीति अपने राष्ट्र की शक्ति आशा से कहीं अधिक बढ़ाती है।"

पुनश्च, मॉर्गेंथो के अनुसार "उत्तम श्रेणी की कूटनीति विदेश-नीति के लक्ष्य तथा साधन का राष्ट्रीय शक्ति के साधनों से सामञ्जस्य स्थापित कर देगी। वह राष्ट्रीय शक्ति के गुप्त स्रोतों की खोज कर लेगी और उन्हें पूर्ण स्थायी रूप से राजनीतिक यथार्थता में परिणत कर देगी। राष्ट्रीय प्रयत्नों को दिशा प्रदान कर वह अन्य तत्त्वों जैसे—औद्योगिक सम्भावनाएँ, सैनिक तैयारी, राष्ट्रीय चरित्र तथा राष्ट्रीय मनोबल, का प्रभाव बढ़ा देगी।"

कूटनीति का अर्थ (Meaning of Diplomacy)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विद्वानों ने कूटनीति का कई अर्थों में प्रयोग किया है। हैराल्ड निबोल्सन के अनुसार कूटनीति शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, जैसे—विदेश-नीति, वार्ता (Negotiation), वार्ता की प्रक्रिया और

मशीनरी, वैदेशिक सेवा की एक शाखा, आदि।¹ निकोलसन के अनुसार कूटनीति का सबसे प्रच्छन्न रूप वार्ता का और सबसे बुरा रूप छल छद्म का है।

निकोलसन द्वारा बताए गए कूटनीति के अधिकांश अर्थों को आर्गेस्की आदि विद्वानों ने अस्वीकार किया है तथापि दो अर्थों—वार्ता एवं वार्ता या समझौते की प्रक्रिया को—सामान्यतः सभी ने स्वीकार किया है।² आर्गेस्की के अनुसार कुशलता, चतुराई और कपट कूटनीति के लक्षण भले हो सकते हैं, किन्तु इन्हें कूटनीति को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं कहा जा सकता। कूटनीति को विदेश-नीति के समकक्ष भी नहीं माना जा सकता। विदेश-नीति का निर्माण राष्ट्रीय हित के अनुरूप तथा परिस्थितियों के सन्दर्भ में होता है जबकि कूटनीति विदेश-नीति का वह अंग है जो उसे सक्रियता प्रदान कर राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति में सहायता देती है। चाइल्ड्स का कथन है कि विदेश-नीति सम्बन्धों का सार है जबकि कूटनीति विदेश-नीति के संचालन की प्रक्रिया है।³ इसी तथ्य को पामर एवं पकिंस ने अन्य शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है कि कूटनीति का कार्य विदेश-नीति के संचालन को मनुष्य और मशीनों प्रदान करना है। एक सार है, दूसरी पद्धति।⁴ आर्गेस्की ने कूटनीति को 'दो या दो से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाले समझौतों की प्रक्रिया' माना है। मैकलेलन, ओलसन तथा सोडरबर्ग के कथनानुसार, "कूटनीति की एक सर्वाधिक मूल परिभाषा यह है कि यह प्रत्येक राज्य के स्थायी प्रतिनिधित्व पर आधारित राष्ट्रों के मध्य सम्पर्क का एक रूप है।" एर्नेस्ट सटोव के अनुसार "कूटनीति स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक राजकीय सम्बन्धों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग है।"⁵

बिबो राइट के मतानुसार, "लोकप्रिय रूप में कूटनीति का अर्थ है किसी सौदे या लेन-देन में चतुरता, धोखेबाजी तथा कुशलता का प्रयोग। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रयुक्त किए जाने वाले अर्थ में यह सौदेबाजी की वह कला है जो राजनीति की उस व्यवस्था में कम मूल्य में अधिक से अधिक सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करती है जिसमें कि युद्ध एक सम्भावना है।"

यदि हम विश्व-विख्यात ज्ञानकोषों की परिभाषाओं पर विचार करें तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार कूटनीति 'अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि-वार्ताओं के संचालन की कला' है। वेबस्टर्स न्यू इंगलिश डिक्शनरी के अनुसार कूटनीति की परिभाषाएँ ये हैं—“(क) राष्ट्रों के मध्य सन्धि-वार्ता संचालन की कला और आचार, जैसे सन्धियों की (बहुधा प्रयुक्त की जाने वाली प्रणालियों और रूपों सहित) व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय समागम के संचालन का कार्य या कला अथवा ऐसे समागम में

1 *Nicolson, H* : *Diplomacy*, pp. 13-14.

2 *Organski* : *op. cit.*, p. 341.

3 *Chilis, J. R.* : *American Foreign Service*, p. 64.

4 *Palmer and Perkins* : *op. cit.*, p. 84.

5 *Ernest Satow* : *Guide to Diplomatic Practice*, p. 1.

कौशल या कुशलता का प्रयोग" एवं (ख) "लाभ प्राप्त करने के लिए कौशल या पटुता का प्रयोग।" अक्सकोर्ड इंगलिश डिक्शनरी के अनुसार—“(क) सन्धि-वार्ता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवस्थापन को कूटनीति कहा जाता है” एवं (ख) “राजदूतों तथा दूतों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवस्थापन और संचालन की विधि” ही कूटनीति है।

कूटनीति वास्तव में एक अनेकार्थीय शब्द है जिसकी कोई सामान्य, संतोषजनक और सर्वसम्मत परिभाषा बठिन है। कूटनीति की प्रकृति को समझते हुए के. एम. पनिकर ने महाभारत के एक वृत्तान्त को उद्धृत किया है जिसमें युद्ध से पूर्व समझौते के लिए कौरवों के दरबार में जाने वाले श्रीकृष्ण से द्रोपदी ने उनके जाने के महत्त्व पर सन्देह प्रकट किया था। उस समय श्रीकृष्ण का उत्तर था कि “मैं कौरवों को तुम्हारा पक्ष सही रूप में समझाने जा रहा हूँ, मैं प्रत्यन करूँगा कि वे तुम्हारी माँगों को स्वीकार कर लें। किन्तु यदि ऐसा न हुआ और युद्ध करना पड़ा तो दुनिया यह समझ जाएगी कि गलत कौन था और इस प्रकार वह हमारे बारे में गलत निर्णय नहीं देगी।”¹ कूटनीति का पूरा रहस्य पनिकर के मतानुसार कृष्ण के इस कथन में निहित है। श्री पनिकर के कथनानुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त ‘कूटनीति’ अपने हितों को दूसरे देशों से अग्रिम रखने की एक कला है।” एक अन्य राजनयज्ञ के शब्दों में, “वास्तव में कूटनीति एक भ्रमसाध्य व्यवसाय है। यह जादू अथवा गृहस्य के परे है। इसे किसी भी अन्य सरकारी कार्य की भाँति एक गम्भीर व्यवसाय के रूप में देखा जा सकता है।”²

कूटनीति की परिभाषाएँ पूर्णतः उपयुक्त इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ इसका अर्थ भी बदलता रहता है। पामर एवं पकिंस ने कूटनीति की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख किया है जो उसके स्वरूप को स्पष्ट करने की दृष्टि से उपयोगी हैं—

(क) कूटनीति एक मशीन की भाँति अपने आप में नैतिक अथवा अनैतिक नहीं है। इसका मूल्य इसको प्रयोग करने वाले के अभिप्रायों और योग्यताओं पर निर्भर करता है।

(ख) ‘कूटनीति’ विदेशी कार्यालयों, दूतावासों, दूतकार्यों, राजपुरुषों तथा विश्वव्यापी विशेष मिशनो के माध्यम से कार्य करती है।

(ग) कूटनीति प्रधान रूप से द्विपक्षीय है, अर्थात् यह दो राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों का कार्य करती है।

(घ) आज अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों, क्षेत्रीय प्रबन्धों और सामूहिक सुरक्षा-प्रत्यनो का महत्त्व बढ़ जाने के कारण कूटनीति के बहुपक्षी रूप का महत्त्व बढ़ गया है।

1 K. M. Panikkar : The Principles and Practice of Diplomacy, pp 6-7.

2 Hugh Gilson : The Road to Foreign Policy, p. 31.

(ड) कूटनीति राष्ट्रों के बीच साधारण मामले से लेकर शान्ति और युद्ध जैसे बड़े-बड़े सभी मामले कूटनीति का विचार क्षेत्र है। जब कूटनीति असफल हो जाती है तो युद्ध या कम से कम एक बड़े संकट का खतरा पैदा हो जाता है।

पेंडलफोर्ड तथा लिटन के शब्दों में—“कूटनीति को प्रतिनिधित्व एवं सौदेबाजी की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा परम्परागत रूप से शान्तिकाल में राज्यों का परस्पर सम्बन्ध कायम रहता है।”

निकोलसन और अनेक विचारक यह मानते हैं कि कूटनीति की असफलता के बाद राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाते हैं और जब युद्ध प्रारम्भ होता है तो कूटनीतिक व्यवहार रुक जाता है। पामर एव पॉक्स इस मन का विरोध करते हुए कहते हैं कि विदेश-नीति की भाँति कूटनीति का उद्देश्य भी देश की सुरक्षा कायम रखना है, इसके लिए वह यथासम्भव शान्तिपूर्ण साधन अपनाती है, किन्तु यदि युद्ध अपरिहार्य बन जाए तो कूटनीति सैनिक कार्यों में प्रत्येक सहयोग प्रदान करती है। युद्ध के समय कूटनीति का कार्य रुक नहीं जाता, बल्कि इसका रूप बदल जाता है। युद्धकाल में कूटनीति का कार्य अधिक बढ़ जाता है। पिछले दो महायुद्धों की घटनाओं के अवलोकन से यह बात स्वतः स्पष्ट है।

कूटनीति एवं विदेश-नीति

(Diplomacy and Foreign Policy)

कूटनीति के स्वरूप को समझने के लिए इसका विदेश-नीति, अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं कूटनीतिक रणनीति से सम्बन्ध और अन्तर समझ लेना आवश्यक है। बहुत से लेखकों ने ‘कूटनीति’ शब्द का प्रयोग विदेश-नीति के पर्यायवाची रूप में किया है जबकि दोनों में अन्तर है। सर विक्टर विलेजली के कथनानुसार “कूटनीति विदेश-नीति नहीं है, वरन् इसे क्रियान्वित करने वाला एक अभिकरण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता। कूटनीति का विदेश-नीति से पृथक् कोई अस्तित्व नहीं है वरन् ये दोनों मिल कर कार्यपालिका की नीति निर्धारित करते हैं—विदेश-नीति द्वारा रणनीति तय की जाती है और कूटनीति द्वारा तकनीकें तय की जाती हैं।”¹ इस प्रकार जहाँ विदेश-नीति वैदेशिक सम्बन्धों की आत्मा है वहाँ कूटनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विदेश-नीति को संचालित किया जाता है। कूटनीतिज्ञों द्वारा अपनी सरकारों की विदेश-नीति के सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए जाते, लेकिन वे अपने प्रतिवेदनों द्वारा इस नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योग देते हैं। विदेश-नीति तय करते समय कूटनीतिज्ञों के प्रतिवेदनों को सदैव ही बहुमूल्य वच्चा माल समझा जाता है।²

हेराल्ड निकोलसन के मतानुसार दोनों का सम्बन्ध राष्ट्रीय हितों के साथ समायोजन करने से है। एक और विदेश-नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं की एक

1 Sir Victor Wilesly : Diplomacy in Fetters, p. 30.

2 Childs, J. R. : op. cit., p. 9.

सामान्य धारणा पर निर्भर है तो दूसरी ओर कूटनीति एक लक्ष्य न होकर साधन है, उद्देश्य न होकर एक तरीका है। यह बुद्धि, समझौता-वार्ता एवं हितों के आदान-प्रदान द्वारा सम्प्रभु राज्यों के बीच संघर्ष को रोकता है। यह एक ऐसा अभिकरण है जिसके माध्यम से विदेश-नीति युद्ध के अलावा अन्य साधनों से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करती है। कूटनीति शान्ति का साधन है। जब समझौता करना असम्भव बन जाता है तो कूटनीति निष्क्रिय बन जाती है और अकेली विदेश-नीति कार्यरत रहती है।¹ यदि एक राज्य अन्य राज्यों के साथ अपने सम्बन्धों में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए सक्षम कूटनीति एवं बुद्धिपूर्ण विदेश-नीति का संगम वांछनीय है।

कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Diplomacy and International Law)

कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बीच भी स्पष्ट अन्तर है। कूटनीति विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का साधन है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय हित से परे अन्तर्राष्ट्रीय कानून-व्यवस्था को सम्मान देता है। कूटनीति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को इसी अर्थ में सम्मान दिया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में व्यवस्था बनी रहे और कूटनीति क्रियाशील रह सके। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के कुछ मौलिक नियमों के अनुपालन से प्रायः ऐसी परिस्थितियाँ कायम रहने में सहायता मिलती है जिनमें कूटनीति समुचित रूप से क्रियाशील हो सके। अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राज्यों के बीच पारस्परिक विश्वास को प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे कूटनीति का आचरण सम्भव बनता है। यदि राज्य, किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा नियम या सदाचार की परवाह न कर, राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि के लिए पूर्णतः कूटनीति का प्रयोग करेंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी और सदैव युद्ध का संकट बना रहेगा।

कूटनीतिक अधिकारों के अधिकार और स्वतन्त्रताएँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय हैं। अग्रत्व का क्रम (Order of Precedence) तथा कूटनीतिक अधिकारियों की श्रेणियाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा तय किए जाते हैं। कूटनीति द्वारा राज्यों के आपसी सम्बन्धों को सुधारने के तरीके एवं सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय हैं, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ में सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधि जिस प्रकार कार्य करते हैं वह कूटनीति का विषय है अन्तर्राष्ट्रीय कानून कूटनीति के साधन के रूप में भी उपयोगी है। यह कूटनीतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए साधन प्रस्तुत करना है। कूटनीतिज्ञों के लिए सामान्य भाषा, प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधा, समझाने-बुझाने का तरीका, विवाद तय करने तथा समझौता करने के मापदण्डों आदि की आवश्यकता रहती है जो उन्हें

अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा उपलब्ध होते हैं। इनके होने से सन्धि-वार्ता सुगम बन जाती है। जिन सन्धियों में अस्पष्टता रहती है वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। सन्धि-वार्ता की प्रक्रिया और रूप भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा तय किया जाता है। कूटनीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं।

जब कूटनीति अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने का प्रयास करती है तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून अनेक प्रकार से उसका सहायक सिद्ध होता है। यह अन्य राज्यों में एक राज्य के अधिकारों की रक्षा करता है, उसकी प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करता है, अन्य राज्यों की नीति को प्रभावित करता है तथा राष्ट्रीय सम्पन्नता की अभिवृद्धि करता है। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने के सभी तरीकों में अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुसरण किया जाता है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून कूटनीति का अत्यन्त उपयोगी साधन है। यह एक दृष्टि से कूटनीति का परिणाम भी है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अधिकांश भाग रिवाजों पर आधारित है। यह कूटनीति द्वारा की गई सन्धि-वार्ताओं एवं सम्मोदा-वार्ताओं की परम्परा को अपने नियमों का आधार बनाता है। सम्मेलनीय कूटनीतिक (Conference Diplomacy) के निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्यतः स्वीकृत अंग बन जाते हैं। कूटनीतिक पत्र-व्यवहारों एवं औपचारिक घोषणाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास किया जाता है। स्पष्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं।¹

कूटनीतिक रणनीति (Diplomatic Strategy)

प्रत्येक देश के राजनीतिज्ञ एवं नेता अपनी सरकार की विदेश-नीति को सामान्य रूपरेखा तैयार करते हैं। इस नीति का नियोजन करते समय वे राजनयिक रणनीति भी तैयार करते हैं क्योंकि विदेश-नीति एवं राजनयिक रणनीति दो भिन्न बातें हैं। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। दोनों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए डॉ. ए. कीसिंगर लिखते हैं—“शान्ति को सीधे रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कुछ परिस्थितियों एवं शक्ति-सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है। अतः कूटनीति को शान्ति की अपेक्षा इन शक्ति-सम्बन्धों की ओर ही प्रेरित होना चाहिए।”² कूटनीति के स्वरूप का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेश-नीति, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक राजनीति से उसके सम्बन्ध की उक्त जानकारी अत्यन्त उपयोगी है। कूटनीति एक गत्यात्मक तत्त्व है। समय की परिस्थितियों में परिवर्तन एवं नवीन विकासों के साथ-साथ इसका स्वरूप भी बदलता रहता है। यह एक विकासशील धारणा है।

कूटनीति के लक्ष्य (Objectives of Diplomacy)

जैसा कि कहा जा चुका है, युद्ध और शान्ति दोनों ही कालों में कूटनीति

1 Quincy Wright : International Law and the United Nations, p. 362.

2 Dr. A. Kissinger : Reflections on American Diplomacy, Foreign Affairs, Oct. 1956.

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का मुख्य साधन है। राष्ट्रीय हित के अन्तर्गत देश की सुरक्षा, जन-कल्याण तथा अन्य लाभ सम्मिलित है और कूटनीति का अन्तिम लक्ष्य इनकी सुरक्षा और अभिवृद्धि है। पनिककर के शब्दों में, "समस्त कूटनीतिक सम्बन्धों का मूलभूत उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना होता है और हर राज्य का मूलभूत हित स्वयं अपनी सुरक्षा करना होता है। परन्तु इस सर्वोपरि लक्ष्य के अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार, देशवासियों की रक्षा आदि भी ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय हैं जिनका ध्यान रखना कूटनीति का उद्देश्य है।"¹

कूटनीति प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्रीय हित की प्राप्ति और अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है, तथापि अपने मूल रूप में यह एक शांतिकालीन साधन है। यदि कूटनीति का अन्त युद्ध में होता है तो इसे कूटनीति की असफलता का द्योतक माना जाता है। किन्तु युद्धकालीन स्थिति में भी कूटनीति विशेष रूप से सक्रिय रहती है क्योंकि युद्ध और शान्ति जैसी गम्भीर समस्याओं को सेनापतियों पर पूरी तरह नहीं छोड़ा जा सकता। शान्तिकाल में कूटनीति प्रत्यक्ष योगदान करती है जबकि शक्ति पृष्ठभूमि में रहती है, किन्तु युद्धकाल में शक्ति आगे रहती है और कूटनीतिक दांव-पेच पृष्ठभूमि में खेले जाते हैं। फिर भी युद्ध के सन्दर्भ में कूटनीति के कार्य बड़े व्यापक हो जाते हैं। द्वितीय महायुद्धकाल में कूटनीतिक सम्मेलनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी और युद्ध सम्बन्धी नीति-निर्णय इन सम्मेलनों में लिए जाते थे। आशय यह है कि कूटनीति विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह करती है और हर समय हर परिस्थिति में इसका मूलभूत लक्ष्य राष्ट्रीय हित का संरक्षण और सम्बर्द्धन होता है। फामर एव पकिस के अनुसार—“विदेश-नीति की भाँति कूटनीति का उद्देश्य, सम्भवतः शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा, लेकिन युद्ध न रोके जा सकने की दशा में सैनिक गतिविधियों की सहायता द्वारा, राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करना है। कूटनीति, जैसा कि निकोलसन ने कहा है, युद्धकाल में समाप्त नहीं हो जाती अपितु युद्धकाल में उसे पृथक् भूमिका निभानी पड़ती है तथा विदेश-मन्त्रियों की तरह कूटनीतिज्ञों का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। इस शताब्दी के दो महायुद्ध इस धारणा की पुष्टि करते हैं।” मॉर्गेन्थो का विचार है कि “यदि नीति के लक्ष्य तथा साधन स्पष्ट रूप से विदित हो तो राष्ट्रीय शक्ति सामान्यतया किन्तु युद्धकाल में विशेष रूप से अपनी तमाम सम्भावनाओं का पूरा सदुपयोग कर उच्चतम शिखर पर पहुँच सकती है।”

के. एम. पनिककर ने राज्यों के कूटनीतिक व्यवहार के प्रमुख सदस्यों का विभाजन किया है जो सक्षेप में निम्नवत् हैं—

1. मित्रराष्ट्रों के साथ सम्बन्धों को मजबूत बनाना और जिन देशों के साथ मतभेद हो उनसे यथासम्भव तटस्थ रहना।
2. अपने राष्ट्रीय हित की विरोधी शक्तियों को तटस्थ बनाए रखना।
3. अपने विरुद्ध दूसरे राष्ट्रों का एक गुट बनने से रोकना।

4. यदि दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध अपने हितों की रक्षा करते समय साम, दाम और भेद—ये तीनों ही नीतियाँ असफल हो जाएँ तो युद्ध का सहारा लिया जाए। किन्तु कूटनीति का कार्य है कि युद्ध ऐसी परिस्थिति में तथा ऐसे रूप में अपनाया जाए कि दूसरे देश यह समझ जाएँ कि तुम्हारा पक्ष न्यायपूर्ण है तथा तुम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हो और भाक्रमणकारी तुम नहीं बल्कि दूसरा पक्ष है।

5. चाणक्य का मत था कि यदि युद्ध और शान्ति दोनों से समान परिणाम प्राप्त होता हो तो शान्ति को अपनाओ, तथा युद्ध और निष्पक्षता का समान लाभ मिल रहा हो तो निष्पक्षता को अपनाओ। युद्ध को तो केवल तभी अपनाना चाहिए जब अन्य सभी साधन असफल हो जाएँ।

6. युद्ध कूटनीति की असफलता का चोकर है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि युद्ध के समय कूटनीति ही समाप्त हो जाती है, बल्कि सच तो यह है कि बिना कूटनीति के न तो युद्ध किए जा सकते हैं और न ही जीते जा सकते हैं। युद्ध से पूर्व गलत कूटनीतिक तैयारियाँ तथा युद्ध के समय की प्रभावहीन कूटनीति 'हार' की निश्चित बना कर शक्तिशाली राष्ट्रों का भी विध्वंस कर देनी है।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कूटनीति निम्न तीन साधनों को काम में ला सकती है—(i) सम्झौता (Persuasion); (ii) समझौता करना (Compromise); एवं (iii) शक्ति प्रयोग की धमकी देना (Threat of Force)। सफल कूटनीति के लिए अपेक्षित है कि जहाँ तक सम्भव हो तब तक वह प्रथम दो साधनों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास करे क्योंकि कोई भी कूटनीति, जो केवल शक्ति की धमकी देकर ही काम निकालना चाहती है, न तो शान्तिप्रिय कही जाएगी और न ही बुद्धिपूर्ण। किन्तु कभी-कभी ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जब शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाए। कूटनीति की कला इसी बात में है कि वह समय व परिस्थिति के अनुसार ही तीनों में से किसी एक का प्रयोग करे।

कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना और मान्यता

द्वारा राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि

(Promotion of National Interest through Recognition and the Establishment of Diplomatic Relations)

जब कोई भी नया राज्य स्वतन्त्रता प्राप्त करके अस्तित्व में आता है तो अन्य देशों की सरकारें सामान्यतया उसे मान्यता प्रदान करती हैं। इसी प्रकार जब कोई नई सरकार बंधानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया से सत्तास्थ होती है अथवा जब राज्य में उसका निर्विवाद प्रभुत्व स्थापित होता है तो अन्य सरकारें सामान्यतया उसे अपनी मान्यता प्रदान कर देती हैं। इस प्रकार की मान्यता देने के कूटनीतिक कदम के पीछे राज्य के अपने हित छिपे होते हैं। मान्यता देने वाली सरकार समझती है कि अमुक राज्य या अमुक सरकार को मान्यता देने अथवा दूसरे राज्यों और सरकारों से कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना करने से उसके हितों का संवर्धन होगा। आज के

विश्व में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और कल्याण प्रांशिक रूप में इस बात पर निर्भर है कि अन्य राज्यों के साथ उसके सम्बन्ध कहीं तक सुनोपजनक हैं।¹ कूटनीतिक सम्बन्धों के माध्यम में एक सरकार नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ हो सकती है, वह अपने लिए एक सम्मानजनक वातावरण का निर्माण कर सकती है और अपनी नीतियों के लिए दूसरे राज्यों का क्रियात्मक समर्थन प्राप्त कर सकती है। कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना द्वारा लाभकारी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। जो नागरिक विदेशों की यात्रा करते हैं और वहाँ अपने व्यापार का विस्तार करते हैं, उनके हितों की भी सुरक्षा हो जाती है। नवोद्भूत बंगलादेश को भारत द्वारा तुरन्त मान्यता देना एक ऐसा प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिक कदम था जिसमें दोनों देशों की प्रगट मंजी के साथ सहमति थी। जब पाकिस्तान और चीन ने बंगलादेश को लम्बे समय तक मान्यता नहीं दी, तो इनका अर्थ था कि बंगलादेश के साथ वे सामान्य सम्बन्धों की स्थापना के पक्ष में नहीं थे। तत्कालीन परिस्थितियों में सम्भवतः दोनों देश यह समझते थे कि बंगलादेश को कूटनीतिक मान्यता न देकर वे अपनी नीतियों की रक्षा कर रहे हैं, बंगलादेश के साथ मौदेवात्री की पृष्ठभूमि मजबूत बना रहे हैं तथा दबाव की राजनीति का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विश्व का बहुमत बंगलादेश के पक्ष में है, विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने बंगलादेश को मान्यता दे दी है तो उन्हें स्पष्ट महसूस हुआ कि बंगलादेश को कूटनीतिक मान्यता न देने के दुराग्रह में वे बदनाम हो रहे हैं, उनके हितों को ठेस पहुँच रही है और फलस्वरूप उन्होंने भी मान्यता दे दी।

कभी-कभी सरकारें अपनी मान्यता अर्जत देती हैं अर्थात् मान्यता प्रदान करने के बदले में किसी 'समर्थन' की माँग करती हैं या कोई 'परिवर्तन' चाहती हैं। जब कभी ऐसा होता है तो प्रायः दूसरी सरकारें, जिनकी नीतियों में अमुक समर्थन या परिवर्तन टकराना है, अपनी आपत्ति प्रकट करती हैं। फ्रांस ने सन् 1778 में संयुक्त-राज्य अमेरिका को मान्यता दी जिसका एक उद्देश्य ब्रिटेन को कमजोर बनाना था। इस मान्यता के साथ एक सन्धि की गई थी जिसका अर्थ था युद्ध में सहभागिता। थियोडोर रुजवेल्ट ने पनामा में फ्रान्स को प्रोत्साहन दिया और ज्योंही फ्रान्स शुरू हुई उसने फ्रान्सिकारियों को मान्यता दे दी और ऐसे अन्य कदम भी उठाए जिनमें नए राज्य की सुरक्षा निश्चित हो जाए। प्रथम महायुद्ध काल में मित्रराष्ट्रों ने बेल्जोम्बोवाजिया के नए राज्य की सरकार को उस समय ही मान्यता दे दी जबकि उसका राज्य के किसी भी क्षेत्र पर वास्तविक नियन्त्रण था ही नहीं। स्पेन के गृह-युद्ध के प्रारम्भ में ही इटली और जर्मनी दोनों ने फ्रांस के फ्रान्सिकारी गुट को मान्यता दे दी और ऐसे अनेक कदम उठाए जिनमें फ्रांसो-गुट की विजय सुनिश्चित हो जाए।

कभी-कभी सरकार मान्यता रोक भी देती है—विशेषकर तब जबकि वह किसी परिवर्तन का विरोध करती है या कोई परिवर्तन न चाह कर यथास्थिति की समर्थक होती है। संयुक्तराज्य अमेरिका का यह खूँसा रहा है कि उसने प्रायः क्रान्तिकारी सरकारों को मान्यता देने में सकोष प्रदर्शित किया है या लम्बे समय तक उन्हें मान्यता नहीं दी है। बहुत से लेटिन अमेरिकी राज्यों को अमेरिका ने किन्हीं समय मान्यता देने से इंकार किया क्योंकि सत्ता-परिवर्तन असांविधानिक तरीके से हुआ था। पर इसका यह मतलब नहीं है कि अमेरिका 'सांविधानिक परिवर्तन' का हिमायती था बल्कि बात यह थी अमेरिका विद्रुली सरकार का पतन नहीं चाहता था अर्थात् नई क्रान्तिकारी सरकार को सत्ताखंड नहीं देखना चाहता था। साम्यवादी चीन के लिए अमेरिकी मान्यता वर्षों तक भ्रष्ट में लटकी रही, यही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐतिहासिक तथ्य है। कभी-कभी यह भी होता है कि दो सरकारों के बीच में कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ देती हैं क्योंकि किन्हीं मसलों पर उनमें कटु विवाद उठ खड़े होते हैं। बंगलादेश की घटनाओं के कारण सन् 1971 में भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद हो गए थे जो अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके हैं।

राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में कूटनीतियों का योगदान (Role of Diplomats in the Promotion of National Interest)

राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए विदेश-नीति के उद्देश्यों तथा कूटनीति के लक्ष्यों की प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व कूटनीतियों पर होता है। राष्ट्रीय हित का संरक्षण और सम्बर्द्धन बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर है कि उस देश के कूटनीतिज्ञ कितने निपुण हैं। उनके कार्यों और महत्त्व को स्पष्ट करते हुए आचार्य कौटिल्य ने अपने विख्यात ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' में लिखा है—“अपनी सरकार के दृष्टिकोण को दूसरी सरकार तक पहुँचाना, सन्धियों की कायम रखना, अपने राज्य के हितों की, यदि आवश्यक हो तो उपा-धमका कर भी, रक्षा करना, मित्र बनाना, फूट डालना, गुप्त सगठन बनाना, गुप्तचरों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो सन्धियाँ अपने राज्य के हित में न हो उन्हें निष्फल बनाना, उस देश के (जिसमें वह नियुक्त हो) शासनाधिकारियों को अपने पक्ष में करना, आदि राजदूत के कर्तव्य हैं।”¹

कौटिल्य ने राजदूत के जिन कर्तव्यों का उल्लेख किया है, सामान्यतः वे सभी आधुनिक कूटनीतिज्ञों के लक्ष्य हैं जिनसे राष्ट्रीय हित-साधन होता है। हम उन्हें आधुनिक राजनयज्ञों में सम्मिलित कर सकते हैं—सरकार के अध्यक्ष विदेश-सचिव तथा उनके विदेश अधिकारी, दूसरे देशों में स्थित कूटनीतिज्ञ कर्मचारी वर्ग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने वाले सैनिक तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा-यंत्र आदि। इनके अतिरिक्त

अन्य लोग भी होते हैं जैसे, भ्रमणशील राजदूत, व्यक्तिगत प्रतिनिधि, सैलानी लोग आदि। कूटनीति और कूटनीतिज्ञों का आज स्थायी महत्त्व स्वीकार कर लिया गया है। यह स्थिति लगभग 15वीं शताब्दी से ही विकासशील है।

राज्य के नाममान के अध्यक्ष जैसे ग्रेट ब्रिटेन के राजा या रानी, भारत का राष्ट्रपति, आदि विदेशी मामलों में मूलतः औपचारिक योगदान करते हैं। वे जब विदेश भ्रमण पर जाते हैं तो उनका उद्देश्य मुख्यतः सद्भावना की अभिवृद्धि होता है। सरकारों के अध्यक्ष अपने देश की कूटनीति में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ट्रूमैन, क्लेवेल्ट, आइजनहाऊवर, कर्नेडी, जानसन, निक्सन आदि सभी अपने देश की सरकार के अध्यक्ष होने के साथ-साथ देश तथा विदेश में सन्धि-समझौते भी करते हैं। यही बात भारत के प्रधान मंत्री नेहरू, फ्रांस के राष्ट्रपति डिगाल, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री चर्चिल, रूस के प्रधान मंत्री स्टालिन आदि के बारे में भी कही जा सकती है।

कूटनीतिक क्षेत्रों में तानाशाहों द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कुछ भिन्न प्रकार का होता है। तानाशाह किसी अन्य माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। वैसे स्टालिन ने मित्रराष्ट्रों के साथ तेहरान, याल्टा, पोर्टस्मथ आदि सम्मेलनों में भाग लिया था, किन्तु साधारणतः वह पृष्ठभूमि में रहता था और अपने विदेश-मन्त्री मोलोटोव (Molotov) के माध्यम से विदेशी मामलों पर नियन्त्रण रखता था। दूसरी ओर प्रधान मन्त्री खुश्चेव ने विश्व-राजनीति में स्वयं सक्रिय रुचि ली और ब्रेझ्नेव, कोसीगिन आदि ने भी यही किया। इसी प्रकार संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर ने मिस्री कूटनीति का उत्तरदायित्व सम्भाला और एक अरब नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की ताकि वह महाशक्तियों के साथ सौदेबाजी करने के लिए सक्षम तटस्थ गुट संगठित कर सकें।

'जैसे को तैसा' एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सिद्धान्त है जो सरकार के अध्यक्षों को एक की पहल पर कूटनीति में खींच लाता है। इस सिद्धान्त के क्रियान्वयन से यह आशा की जाती है कि सरकार के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी नेता कूटनीति में आज की भाँति ही सक्रिय रहेंगे। इस नीति का एक उदाहरण हम प्रधान मन्त्री कोसीगिन के उस आमन्त्रण को मान सकते हैं जो उन्होंने भारतीय प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान को उनके आपसी मतभेद मिटाने के लिए ताशकन्द में आने के लिए भेजा था। इस आमन्त्रण को दोनों ही देशों के नेता नहीं ठुकरा सके।

कूटनीति के क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय कार्यकर्त्ता विदेशी मामलों के राज्य-सचिव होते हैं। विदेश-मन्त्र्य उनका मुख्य कार्य है। वे जीवन भर कूटनीतिक वार्ताएँ करते हैं, अन्य देशों के दौरे करते हैं, सम्मेलनों में उपस्थित होते हैं तथा महत्त्वपूर्ण सौदेबाजियों की तैयारी करते हैं। वे अपने राज्याध्यक्षों को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा विदेशी मामलों के सम्बन्ध में उनको सूचित करते रहते हैं। अपने विदेश-कार्यालय एवं विदेश-सेवा की बहुत बड़ी नीगरनाही पर शासन

करना भी उनका उत्तरदायित्व है। वे मन्निमण्डल तथा अन्य नीति सम्बन्धी बैठकों में उपस्थित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश-सचिवों ने मन् 1945 के बाद अपना अधिकांश समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उपस्थित रहने में व्यतीत किया। अनुमानतः यह कहा जाता है कि जॉन फॉस्टर डलेस (John Foster Dulles) ने अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में प्रति वर्ष एक लाख हवाई मील से भी अधिक की यात्रा की। इतनी लम्बी यात्रा करके वे चाँद तक जाकर वापस आ सकते थे। यही सारी यात्रा उन्होंने दुनिया के अन्य नेताओं के साथ बातचीत के लिए की। विदेश-सचिव डीन रस्क ने स्वयं अधिक यात्रा करने की अपेक्षा यह उचित समझा कि दूसरे लोग ही वाशिंगटन आएँ। वर्तमान विदेश मन्त्री डॉ हेनरी किस्सिजर को तो मानों कूटनीतिक यात्राओं के पर लग गए हैं। उन्हें आज के युग का एक कटिमायात्री कूटनीतिज्ञ माना जाता है।

आज कूटनीति में सलग्न अनेक लोग ऐसे हैं जिनको हम व्यावसायिक विशेषज्ञ कह सकते हैं। इनमें हम नागरिक सेवकों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित करेंगे जो विदेशों में दूतावासों एवं देश में विदेश कार्यालय में कार्य करते हैं। ये अधिकारी विदेशी सम्बन्धों के प्रचलित पहलुओं को सम्पादित करते हैं। ये अध्ययन, प्रतिवेदन एवं निर्देशन तैयार करते हैं। ये दूसरे देशों के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ विचार करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाने वाले प्रतिनिधि-मण्डल के स्टाफ का काम करते हैं। उनके कार्य मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं—प्रथम यह कि अपने मालिकों के काम को सम्पन्न करें और दूसरा यह कि दूसरों के कार्यों का पता लगाएँ। व्यावसायिक विशेषज्ञों का यह दल एक दिन में संगठित नहीं हो जाता। आज के युग की परिस्थितियों में एक योग्य विदेश-सेवा के विरासत में लिए पर्याप्त समय एवं अनुभव की आवश्यकता होती है।

सरकारें समय-समय पर विशेष गुप्त दूत (Emissary) नियुक्त करती हैं जो महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष समझौते करते हैं तथा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंक्लिन रूजवेल्ट ने हैरी हार्पकिंस (Harry Hopkins) को अपना विश्वास प्रदान किया और राज्य-सचिव तथा सम्बन्धित राजधानियों के राजदूतों की अवहेलना उनके कई बार चर्चित और रटालिन के पास गुप्त वार्ता के लिए भेजा। इसी प्रकार राष्ट्रपति आइज़नहावर ने अपने भाई मिल्टन आइज़नहावर को अनेक विशेष अवसरों पर प्रयुक्त किया। राजदूत एवरन हैरीमैन (Averell Harriman) को राष्ट्रपति ट्रूमैन, कनेडी और जॉन्सन द्वारा द्रष्टेक विशेष अवसरों पर नियुक्त किया गया। राज-सचिव बनने से तीन वर्ष पूर्व जॉन फॉस्टर डलेस को जापान की शान्ति-सन्धि में वार्तालाप का काम सौंपा गया। ये सारी नियुक्तियाँ राज्य के अध्यक्ष के विशेषाधिकार हैं। यह हो सकता है कि कुछ देशों को प्रभावित करने वाले क्षेत्र की किसी विशेष समस्या में गुप्त दूत राजदूत की अपेक्षा अधिक कुशल हो। किन्तु फिर भी सम्भावना यह रहती है कि वह उस देश के राजदूत के प्रभाव एवं सम्मान को कम कर देगा और ऐसी स्थिति में इस तकनीक का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

आज के जटिल वातावरण में राज्यों के आपसी सम्बन्ध राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षात्मक एवं वैज्ञानिक अनेक विषयों से युक्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि सरकारी के विभिन्न विभागों के सेवीयों को कूटनीतिक सम्बन्धों में तथा नीति-निर्माण में भाग लेने का अवसर दिया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सर्वाधिक सक्रिय रूप से भाग लेने वालों में सशस्त्र सेनाओं एवं सुरक्षा संस्थानों के सदस्य होने हैं। नाटो देशों के सुरक्षा-सचिव तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी जब नाटो की बैठकों में नए सुरक्षा प्रबन्धों पर विचार करते हैं, तो एक प्रकार से कूटनीति में उलझ जाते हैं। इसी प्रकार जब जन-स्वास्थ्य अधिकारी विश्व-स्वास्थ्य संगठन (W. H. O.) की बैठक में भाग लेते हैं या राजकोष के प्रतिनिधि विश्व-बैंक की बैठक में भाग लेते हैं तो वे भी कूटनीति में उलझ जाते हैं। इसी प्रकार से पारस्परिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक एवं तकनीकी सहायता कार्य आदि भी किसी न किसी प्रकार से कूटनीति से सम्बन्ध रखते हैं। पीयरसन के कथनानुसार अफगानिस्तान में संयुक्तराज्य अमेरिका का भू-वैज्ञानिक संयुक्तराज्य अमेरिका की नीति के बारे में अमेरिकी राजदूत की अथवा अफगानिस्तान के मत को अच्छे या बुरे के लिए अधिक प्रभावित कर सक्ता है।

कूटनीतिक विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ (Diplomatic Privileges and Immunities)

आधुनिक युग में कूटनीतिज्ञों को अनेक विशेषाधिकार और स्वतन्त्रताएँ दी जाती हैं ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों का भली प्रकार निर्वहन कर सकें। सामान्यतः निम्नलिखित विशेषाधिकार और स्वतन्त्रताएँ आवश्यक रूप से प्रदान की जाती हैं—

(1) व्यक्तिगत सुरक्षा, (2) फौजदारी कानून के क्षेत्राधिकार से मुक्ति, (3) दीवानी कानून के क्षेत्राधिकार से मुक्ति, (4) राजनयिकों से सम्बन्धित लोगों की स्वतन्त्रताएँ, (5) निवास-स्थान से सम्बन्धित विशेषाधिकार, (6) कगरे से मुक्ति, एवं (7) संचार-साधनों की स्वतन्त्रता।

पामर एवं पकिंस के मतानुसार इन विशेषाधिकारों और स्वतन्त्रताओं को देने के मूल में दो महत्वपूर्ण कारण हैं—प्रथम यह कि कूटनीतिज्ञ अपने राज्य के अधिभों के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं और साथ ही अपनी सरकार तथा अपने देश की जनता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे, वे अपने कार्यों को सन्तोषजनक रूप से तभी सम्पन्न कर सकते हैं जब स्थानीय कानून द्वारा आरोपित कुछ बाधाओं से उन्हें मुक्त रखा जाए।

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए कूटनीति के मूलभूत कार्य (Substantive Functions of Diplomacy for the Promotion of National Interest)

कूटनीति वा अन्तिम लक्ष्य राष्ट्रीय हित का संवर्द्धन तथा निर्धारित नीति के उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न है। कूटनीतिज्ञ राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्टॉलिन ने कूटनीति को एक प्रकार की कला मानते

हुए कहा या कि कूटनीतिज्ञ के शब्दों का उसके कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा है तो वह कूटनीति ही कौसी ? 'कबनी' एक चीज है और 'करनी' दूसरी । अन्धे शब्द बुरे कार्यों को छिपाने में दास का काम करते हैं । एक निष्कपट कूटनीति उसी तरह असम्भव है जिस तरह कि 'सूखा पानी' या 'गरम सोहा' ।¹

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि सम्बन्धी कूटनीति के मूलभूत कार्यों को विभिन्न विचारकों, राजदूतों और राजनीतिज्ञों ने विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है ।

(क) हिन्दू नीति-शास्त्रों का मत

हिन्दू नीति-शास्त्रों में चार प्रकार के कूटनीति के साधन और उपाय बनाए गए—साम, दान, दण्ड और भेद । 'साम' के अनुसार एक देश मित्रतापूर्ण व्यवहार सुझाव एवं धोड़िक तर्कों द्वारा अपने राष्ट्रीय हित साधन का प्रयास करता है । 'दान' के अनुसार एक देश अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धन व्यय करता है । ऐसे समझौते करता है जिसमें स्वयं के धन से दूसरे पक्ष का लाभ हो । कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ देना, कुछ व्यय करना आवश्यक बन जाता है । यह समझौते का एक तरीका है । जहाँ साम और दान से काम बनता न दीखता हो वहाँ 'भेद' का सहारा लेना होता है अर्थात् शत्रु के शत्रु से मिल कर लेना और शत्रु के मित्रों में आपस में फूट डाल देना । कूटनीति का सबसे अन्तिम हथियार शक्ति है । जब सभी अन्य साधन असफल हो जाएँ तो कूटनीति को युद्ध का मार्ग अपना पड़ता है ।

(ख) सरदार पनिक्कर का मत

कूटनीतिज्ञ को एक देश का दूसरे देश में स्थित भाँत और कान कहा जाता है । कोई भी देश अपने कूटनीतिज्ञों के माध्यम से दूसरे देश की घटनाओं, नीतियों और दृष्टिकोणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर अपनी विदेश-नीति को आवश्यक मोड़ देता रहता है । बहुत से विचारकों ने चातुर्य, कुशलता, कपट आदि को कूटनीतिक गुण माना है जबकि ख्यातिप्राप्त भूतपूर्व भारतीय राजदूत पनिक्कर के अनुसार घूर्तता, कपट आदि से पूर्ण कूटनीति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कम सहायक हो सकती है । कारण यह है कि कूटनीति अपने देश के प्रति दूसरे देशों की शुभ कामना प्राप्त करने की दृष्टि से प्रेरित होती है और कपट आदि इस उद्देश्य के मार्ग में खतरनाक साधन हैं । दूसरे देशों की शुभ कामना प्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति चार प्रकार से अधिक अच्छी तरह हो सकती है—दूसरे देश उस देश की नीतियों को ठीक प्रकार से समझे और उसके प्रति सम्मान की भावना रखें, वह देश दूसरे देशों की जनता के न्यायोचित हितों को समझे एवं सर्वोपरि, वह ईमानदारी से व्यवहार करें । आप बहुत से लोगों को सदा के लिए धोखे में नहीं रख सकते और इस दृष्टि से चातुर्य, कपट आदि से पूर्ण कूटनीति के पदों में जब छिद्र हो जाएँगे और देश की

नीति की असतियत जाहिर हो जाएगी तो विश्व-समाज में उस देश के स्तर को बड़ा धक्का पहुँचेगा। पनिक्कर जैसे विचारकों का मत है कि व्यक्तिगत जीवन की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।

(ग) पामर एवं पर्विस का मत

पामर एवं पर्विस ने कूटनीतिज्ञ को दूसरे देशों में अपनी सरकार की आँख और कान (Eyes and ears of his Government) कहा है जिसके मुख्य कार्य हैं—अपने देश की नीतियों को क्रियान्वित करना, अपने देश के हितों और देशवासियों (जो विदेश में हों) की रक्षा करना तथा अपनी सरकार को शेष विश्व में सोने वाली मुख्य घटनाओं के बारे में सूचित रखना।¹ कूटनीतिज्ञों के कार्यों को भागे चलकर और भी स्पष्ट करते हुए पामर एवं पर्विस ने इन्हें चार आधारभूत वर्गों में विभाजित किया है—(1) प्रतिनिधित्व (Representation), (2) समझौता-वार्ता (Negotiation), (3) प्रतिवेदन (Reporting), एवं (4) विदेशों में अपने राष्ट्र और अपने देश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा (The Protection of the interests of the Nation and of its Citizens in Foreign Land)। एक अन्य स्थल पर लेखकद्वय ने लिखा है कि विदेश-नीति की भाँति ही कूटनीति का यह लक्ष्य है कि यथासम्भव शान्तिपूर्ण साधनों से देश की रक्षा करे, लेकिन यदि युद्ध अपरिहार्य हो जाए तो संनिव तैयारी कर युद्ध करे। युद्ध के समय 'शान्तिवालीन कूटनीति' का रूप बदलकर युद्ध की अवस्थाओं के अनुरूप हो जाता है।

(घ) विबन्सी राइट, ओपेनहेम, चाइल्ड्स तथा

पेंडलफोर्ड एवं लिंकन का मत

विबन्सी राइट के अनुसार कूटनीति युद्ध से भिन्न इसलिए है क्योंकि यह भौतिक शक्तों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करती है। शक्ति-प्रदर्शन और युद्ध की धमकी कूटनीति के साधन हैं पर जब युद्ध छिड़ जाता है तो दोनों पक्षों में दोष प्रायः कूटनीतिक सम्बन्ध टूट जाते हैं। ओपेनहेम ने कूटनीतिज्ञों के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया है—(i) समझौता (Negotiation), (ii) पर्यवेक्षण (Observation) एवं (iii) सुरक्षा (Protection)। चाइल्ड्स ने भी पामर एवं पर्विस की भाँति ही कूटनीतिज्ञों के कार्यों को इन चार भागों में बाँटा है—(1) प्रतिनिधित्व करना, (2) समझौता करना, (3) प्रतिवेदन करना, एवं (4) विदेशों भूमि में अपने देश के नागरिकों तथा देश के हितों की रक्षा करना। पेंडलफोर्ड एवं लिंकन ने भी चार कार्यों को ही प्रमुखता दी है—सुरक्षा, प्रतिनिधित्व, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन तथा समझौता।

(ङ) मार्गेन्यो का मत

मार्गेन्यो के अनुसार कूटनीतिज्ञ के अप्रतिष्ठित चार प्रमुख कार्य हैं—प्रथम राज्य की शक्ति को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना; द्वितीय, अपने

उद्देश्यों और राज्य-शक्ति के साथ-साथ दूसरे राज्य की शक्ति का समुचित मूल्यांकन, तृतीय, यह पता लगाना कि विभिन्न राज्यों के लक्ष्य एक दूसरे से कहाँ तक मेल खाते हैं और यदि इन लक्ष्यों के मध्य साम्य न हो तो उनके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करना एवं चतुर्थ, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समझौता, समझाना-बुझाना, बलप्रयोग की धमकी आदि उपायों का आश्रय लेना।

(च) लियो बी पौलाद का मत

एक भूतपूर्व अमेरिकी राजदूत लियो बी पौलाद (Leon B. Poullada) ने अपने एक लेख 'Diplomacy : The Missing Link in the Study of International Politics' में कूटनीति के पाँच कार्यों का उल्लेख किया है¹ --

1. संघर्ष का प्रबन्धन (The Management of Conflict)
2. समस्या-समाधान (Problem-solving)
3. परा-सांस्कृतिक कार्य (Trans-cultural Functions)
4. समझौतावार्ता और सौदेबाजी (Negotiations and Bargaining)
5. कार्यक्रम व्यवस्था (Programme Management)

संघर्ष का प्रबन्ध (The Management of Conflict)—कूटनीतिज्ञ का एक प्रमुख मूलभूत कार्य संघर्ष का प्रबन्धन है अर्थात् जहाँ कहीं हितों का भारी कटाव (Intersection of Interests) हो वहाँ एक कूटनीतिज्ञ को समझाने-बुझाने, सौदेबाजी करने, सुलह कराने आदि विभिन्न उपायों द्वारा संघर्षपूर्ण स्थितियों के समाधान में प्रवृत्त होना चाहिए। घरेलू क्षेत्र में पेशेवर राजनीतिज्ञ जिस प्रकार इन कार्यों का निर्वहन करते हैं उसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में कूटनीतिज्ञ इन कार्यों का निर्वहन विभिन्न संस्कृतियों और मूल्य-व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में करते हैं और इस हैसियत से वे मुख्यतया एक 'परा-सांस्कृतिक संघर्ष दलाल' (Trans-cultural Conflict Broker) की भूमिका निभाते हैं। एक कूटनीतिज्ञ यद्यपि प्रधान रूप से अपने देश के हितों का अधिनिधित्व करता है लेकिन वह इस बात से भी परिचित होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी पक्ष पूर्ण 'सही' होने का दावा नहीं कर सकता और बहुधा ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जब हितों में सामञ्जस्य बैठाना पड़ता है। कूटनीतिज्ञ विभिन्न हितों के प्रसारकों में इस तरह सामञ्जस्य बैठाने का प्रयत्न करता है कि सभी सम्बन्धित पक्षों को शुद्ध लाभ (Net Gain for All Concerned) प्राप्त हो। खेल सिद्धान्त के रूप (Game Theory Targon) कूटनीतिज्ञ सदैव एक 'नान-जीरो-सम गेम' (A Non-zero-sum Game) के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस भूमिका में वह तभी सफल हो सकता है जब विभिन्न पक्षों के सांस्कृतिक अनुदेशों, निर्णायकारी शक्ति के स्रोतों, शक्ति-संचासकों के सही दावपेचों आदि को भली प्रकार समझ कर कार्य करे। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष-प्रबन्धन

1 Leon B. Poullada's Article in "The Theory and Practice of International Relations", 1974, pp. 196-199 by David Mclellan, W. C. Olson and Fred A. Sondermann.

निरोधात्मक कूटनीति (Preventive Diplomacy) का बहुत ही महत्त्वपूर्ण व्यवहार है, तथापि इसकी खोजबीन उतनी ही कम की गई है जितनी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में इस पहलू के अध्ययन की उपेक्षा की गई है। एक कूटनीतिज्ञ को राबर्ट नार्थ के इन शब्दों की समझना चाहिए कि “संघर्ष के तीव्रीकरण को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि सर्वप्रथम संकट के विकास को टाला जाए।”¹

समस्या-समाधान (Problem-solving)—मूलभूत कूटनीतिक गतिविधि का दूसरा क्षेत्र समस्या-समाधान है। विदेश-सम्बन्धों के संचालन में अनेक समस्याएँ घोर कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं तथा कई बार सीमान्त परसन्धिगम्यो (Marginal Choices) को चुनने की स्थिति उत्पन्न होती है अतः कूटनीतिज्ञ का प्रतिवेदन सम्बन्धी काम सुगम नहीं होता। देखने में प्रतिवेदन तथ्यों के सग्रह का सीधा साधा काम लगता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से समस्या-समाधान का एक अभ्यास-क्रम है। कूटनीतिज्ञ को चाहिए कि वह सर्वप्रथम विभिन्न सम्भव व्याख्याओं में से चुनाव करे, सूचना-सग्रह में से विभिन्न सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों या पक्षपातों की छँटना कर दे और उपलब्ध सूचना को प्रयोग में लाने का बहुत ही रचनात्मक तरीका चुने ताकि नीति-निर्माण और क्रियान्वयन दोनों को प्रभावित किया जा सके। समस्या-समाधान की दिशा में गम्भीर सैद्धान्तिक कार्य किसी भी कूटनीतिज्ञ के लिए मूल्यवान है क्योंकि इससे न केवल संघर्ष प्रबन्धन (Conflict Management) में सहायता मिलती है बल्कि सहयोग को उन क्षेत्रों में भी जिनमें हितों का कोई संघर्ष नहीं होता समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है।

परा-सांस्कृतिक कार्य (Trans-cultural Functions)—मूलभूत कूटनीतिक गतिविधि का तीसरा क्षेत्र कूटनीतिक व्यवसाय के परा-सांस्कृतिक कार्यों पर केन्द्रित है। कूटनीतिज्ञ के कार्यों का यह पहलू उसके व्यवसाय को एक अद्भुत स्वरूप प्रदान करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी कूटनीतिज्ञ परा-सांस्कृतिक कार्यों में निपुण होते हैं। इसका आशय केवल यही है कि उन्हें इस कार्य में निपुण होना चाहिए। पौलाद ने इस सम्बन्ध में रोसो (Rossow) के एक लेख का उद्धरण प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है—“कूटनीतिज्ञ स्वयं को विभिन्न संस्कृतियों के बीच कार्य करते हुए पाता है और कभी-कभी तो अनेक संस्कृतियों के बीच एक साथ ही कार्य-व्यस्त रहता है। कूटनीतिज्ञ का मुख्य योगदान उसकी इस निपुणता में प्रकट होता है कि वह विभिन्न संस्कृतियों के मध्य किस प्रकार अपनी व्याख्याओं पर पहुँचता है। वह इस सम्बन्ध में दो दिशाओं में अपनी निपुणता का प्रयोग कर सकता है—प्रथम, वह विदेशी सांस्कृतिक सन्दर्भों में अपने देश की स्थितियों और विकास की व्याख्या करता है और उन्हें फिट बैठता है, तथा द्वितीय, वह विदेशों में अपने देश के नीति-उद्देश्यों की व्याख्या करता है, उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है।” विभिन्न

1 “The best way to avoid escalation of conflict is to avoid the development of a crisis in the first place.”

—Robert North, Quoted from Leon B. Poullada : Ibid, p. 196.

संस्कृतियों के मध्य कार्य करते हुए भी कूटनीतिज्ञ अपने राष्ट्रीय हित के सम्बर्द्धन में लगा रहता है। अन्योन्य सांस्कृतिक व्यवस्था (Cross-Cultural Interpretation) कूटनीतिज्ञ का एक आधारभूत व्यावसायिक कार्य है।

समझौता-वार्ता और सौदेबाजी (Negotiation and Bargaining)—कूटनीति का चौथा मूलभूत कार्य समझौता-वार्ता और सौदेबाजी है। समझौता-वार्ता केवल अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ़ेंसों में ही नहीं होती बल्कि कूटनीतिज्ञ अपने दैनिक कार्यों में विभिन्न तरीकों से विचार-विमर्श, सौदेबाजी और समझौते सम्बन्धी कार्यों में लगा रहता है। एक छोटे घरातल पर आरम्भ में वह जिस सहयोगपूर्ण और मंत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करता है वही वातावरण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बृहत्तर रंगमंच पर सहयोग और मंत्री के लिए आधार-स्थल का काम करता है।

कार्यक्रम-व्यवस्था (Programme Management)—कुछ दृष्टियों से यह कार्य लोक-प्रशासन का प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीतिज्ञ इस कार्य द्वारा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए तथा सहयोग और मित्रता के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। विदेशों में अपने देश के किराी कार्यक्रम के प्रबन्ध की कुशलता का विदेशी-सम्बन्धों के संवाहन पर काफी प्रभाव पड़ता है। उसके माध्यम से विदेशों में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाती है। आज के युग में इस प्रकार के कार्यक्रमों का महत्व द्वि-राष्ट्रीय और बहु-राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है।

(छ) सामान्य निष्कर्ष

यद्यपि विद्वानों ने कूटनीतिज्ञों के प्रमुख कार्यों की विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यवस्था की है और अलग-अलग रूप से किसी विशेष कार्य को अधिक महत्व दिया है, तथापि कुल मिलाकर कार्यों के बारे में कोई विशेष मतभेद नहीं है। अतः यह उचित होगा कि अलग-अलग विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कार्यों को अलग-अलग व्याख्या न करके सामूहिक ढंग से प्रमुख कार्यों की व्याख्या की जाए।

सुरक्षा (Protection)—सभी विद्वानों के अनुसार एक कूटनीतिज्ञ का यह प्रमुख कार्य है कि वह अपने देश के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करे और उनको प्रोत्साहन दे तथा विदेशों में रहने वाले अपने देशवासियों के अधिकारों की रक्षा करे। उसे नित्यप्रति की घमकियों अथवा असमानताओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि उसके देश के सम्मान के प्रति कोई सौदेबाजी न हो। यह उत्तरदायित्व प्रतिनिधित्व, समझौता, सन्धि एवं कार्यपालिका की सहमति द्वारा पूरा किया जा सकता है। कूटनीतिक मिशन के अधिकारियों को उन लोगों से बातचीत करने होती है जो सहायता की माँग करते हैं तथा जिनके अधिकारों को छीना गया है, सम्पत्ति जब्त कर ली गई है या उनके व्यक्ति हताहत हुए हैं अथवा उन्हें पूरी कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में ये कूटनीतिज्ञ उनके कष्टों को दूर करने में पूरा सहयोग देते हैं। जब राजनीतिक परिस्थितियाँ अस्त-व्यस्त होती हैं तो यह सुरक्षात्मक कार्य एक भारी उत्तरदायित्व बन जाता है और

दूतावास शरणाधिकारियों का आश्रयस्थल बन जाता है। जिस समय गृह-युद्ध या अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की सम्भावना हो अथवा छिड़ रहा हो उस समय कूटनीतिक मिशनो से उसकी शक्ति-भर वह सब करने की आशा की जाती है जिससे उनके राष्ट्र के लोग अपने घर सुरक्षित लौट जाएँ अथवा सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएँ। जब युद्धरत देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध टूट जाते हैं तो परम्परागत रूप से तटस्थ देशों के राजनयिकों से यह कहा जाता है कि वे वहाँ उनके देशवासियों के हितों की रक्षा करें। प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय स्विट्जरलैण्ड तथा स्वीडन ने सुरक्षात्मक एवं मध्यस्थता का यह कार्य किया था।

प्रतिनिधित्व (Representation)—प्रत्येक कूटनीतिज्ञ का यह उत्तरदायित्व है कि उसे चाहे दूसरे राज्यों में भेजा जाए अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में, वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगा और अपनी सरकार तथा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। एक प्रतिनिधि के रूप में कूटनीतिज्ञ अपने राज्य और सरकार का प्रतीक होता है और उनके विचारों को स्पष्ट करता है। यदि दूसरे देश के अधिकारी या गैर-सरकारी व्यक्ति एवं समूह एक देश के दृष्टिकोण तथा अभिप्रायों को जानना चाहते हैं तो वे कूटनीतिज्ञों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। कूटनीतिज्ञ अपने देश के दृष्टिकोण एवं अभिप्रायों को बढ़ी चतुरता, स्पष्टता एवं सक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करता है। उसके व्यक्तिगत विचार चाहे कुछ भी हो, किन्तु दूसरे देशवासियों को वह उन्हीं विचारों को बतलाएगा जो उसके देश की सरकार के हैं। अपनी सरकार के प्रतीक और प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुए राजदूत विदेश में अपने देश के लिए मित्रता की वृद्धि करता है और इसके लिए वह सरकार के नेताओं एवं व्यापार, समाज शिक्षा और राजनीतिक जीवन के नेताओं के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाता है। एक कूटनीतिज्ञ के उत्तरदायित्व का वर्णन करते हुए जोसेफ सी. सी. क्रू (Joseph C. C. Crew) का कथन है कि "उसे सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से एक व्याख्याता (Interpreter) होना चाहिए।" वह व्याख्याता का कार्य दोनों तरीकों से कर सकता है। प्रथम, वह जिस देश में कार्य कर रहा हो उस देश की परिस्थितियों, मनोदशा, कार्य और उसके मूल अभिप्रायों को समझेगा और उनसे अपनी सरकार को परिचित कराएगा। दूसरी ओर वह जिस देश में रह रहा है उसकी सरकार और जनता को अपने मूल देश के उद्देश्य, आशा एवं इच्छाओं से अवगत कराएगा। वह उन विचारों और शक्तियों के बीच पारस्परिक सामञ्जस्य स्थापित करने वाला एक अभिकरण है जिसके आधार पर राष्ट्र कार्य करते हैं। प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि कूटनीतिक मिशन के सदस्य अपने स्वयं के देश के बारे में अच्छी प्रकार से सूचित हो और जहाँ आवश्यकता हो वे निरन्तर और तुल्य सूचना प्रदान करें। जब सार्वजनिक सभाओं में बोलने का अवसर प्राप्त करें तो व्यापार एवं गृहनीति के सम्बन्ध में अपनी नीतियों को स्पष्ट करें, सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रगति का उल्लेख करें तथा अपने देश की कला की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दें।

वरिष्ठ कूटनीति एवं कूटनीतिक मिशन के अध्यक्ष महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे यात्रा के माध्यम से पूरे देश की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वे अन्य राजदूतों के सम्मान में स्वयं भोज देते हैं और दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले भोजों में सम्मिलित होते हैं। हेराल्ड सीमर (Harold Seymour) के अनुसार एक अच्छा भोज कूटनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।

अधिकांश देश अपने कूटनीतिज्ञों को खर्च करने के लिए पर्याप्त धन देते हैं ताकि वे अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकें। संयुक्तराज्य अमेरिका में पहले इस बात पर जोर दिया जाता था और इसलिये कूटनीतिक पद उस व्यक्ति को सौंपे जाते थे जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो, किन्तु अब नए समायोजन के कारण अन्य अधिकारी भी इन पदों को सम्भाल सकते हैं। परम्परागत रूप से अपने देश का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते राजदूत प्रायः प्रमुख प्रशासकीय एवं प्रबन्धात्मक उत्तरदायित्वों को पूरा करता है।

पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन (Observation and Reporting)—कूटनीतिज्ञों को विदेशों में स्थित एक देश के घाँव और कान कहा जाता है। वे विदेशी मामलों के विवेकपूर्ण संचालन में अपनी सरकार को सक्षम बनाते हैं तथा उन्हें इस बात की भी जानकारी देते हैं कि कहां उनके मित्र हैं और कहां उनके विरोधी हैं। विदेशों में काम करने वाले प्रत्येक मिशन का यह प्रधान कर्त्तव्य होता है कि वह अपने देश को निरन्तर प्रतिवेदन भेजता रहे। ये प्रतिवेदन अनेक विषयों पर भेजे जाते हैं जैसे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सैनिक परिस्थितियाँ, विचाराधीन व्यवस्थापन, नवीन उत्पादन एवं उद्योग, तकनीकी प्रगतियों तथा शैक्षणिक परिवर्तन आदि।

इसके अतिरिक्त सरकार को विकासशील मामलों पर समझौते की प्रवृत्तियों तथा महत्वपूर्ण नेताओं, उत्तरदायी अधिकारियों एवं लोकमत पर प्रभाव डालने वालों के राजनीतिक दृष्टिकोणों का महत्व आदि जानने की भी जरूरत रहती है। एक देश के अन्य राज्यों से कैसे सम्बन्ध हैं, सरकार यह जानने के लिए भी प्रयत्नशील रहती है। कूटनीतिज्ञ इन सूचनाओं को केवल तभी भेज सकते हैं जबकि वे सूचना के सभी स्रोतों का तथा सांख्यिकीय आँकड़ों का निरन्तर अध्ययन करते रहें। इन सारी सूचनाओं को एकत्रित करने एवं मूल्यांकित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है। औपचारिक कूटनीतिक प्रतिनिधियों से यह आशा नहीं की जाती कि वे दूसरे देश में जाकर गुप्तचर का कार्य करेंगे यद्यपि उनका देश दूसरे साधनों से यह कार्य कर सकता है। गुप्तचर का कार्य उन देशों में जरूरी बन जाता है जहाँ तथ्यों को छिपाया जाता है और सरकार जानबूझकर वास्तविकता पर पर्दा डालती है, किन्तु जब एक देश में पर्याप्त सूचना, उचित अधिकारियों, सरकारी एवं गैर-सरकारी स्रोतों तथा अन्य प्रकार से प्राप्त हो जाती है, वहाँ गुप्तचरी को आवश्यक नहीं समझा जाता। अमेरिकी लेखकों के मतानुसार साम्यवादी देश अपने कूटनीतिक अधिकारियों द्वारा गुप्तचरी किए जाने से एतराज नहीं करते। इसी कारण एजिप्ता और अफ्रीका के अनेक देशों ने चीनी कूटनीतिक अधिकारियों को

अपने देश से निकाल दिया था। साम्यवादी देशों ने भी अनेक ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि सयुक्त-राज्य अमेरिका का सी. आई. ए. विदेशों में सक्रिय है। भारत में सी. आई. ए. की क्रियाओं के प्रति हाल ही में पर्याप्त विवाद उठा था जिसमें यह कहा गया था कि सी. आई. ए. ने अपने धन द्वारा चतुर्य आम चुनावों को प्रभावित किया और अनेक शैक्षणिक संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं को प्रभावित किया।

समझौता-वार्ता (Negotiation)—कूटनीतिज्ञ का अन्तिम कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राजदूत जॉर्ज केनन (George Kennan) ने इसे केन्द्रीय कूटनीतिक कार्य कहा है। यह कार्य है सरकारों से समझौते की वार्ता करना। चाहे कूटनीतिज्ञ व्यक्तिगत रूप से एक राज्य के साथ समझौते की वार्ता करे अथवा एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अनेक राज्यों के साथ वार्ता करे, उसका यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने देश का पक्ष प्रस्तुत करे। यद्यपि कूटनीतिज्ञ अपने देश तथा अन्य देश के विवाद को भुलभाने का प्रयास करता है, तथापि हम उसे मध्यस्थ नहीं कह सकते। वह केवल कुछ ही मामलों में ऐसा कर सकता है। वह तो अपने पक्ष के लिए सीदेबाजी करता है और समझौता बरते समय वह एक पक्ष की ओर पूरी तरह से झुका रहता है। वह अपने पक्ष के लिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब कूटनीतिज्ञ अपने देश के पक्ष निरन्तर प्रस्तुत करता है तो दूसरे देश के लोगों पर उसका प्रभाव जाने या अनजाने पड़ता ही है।

समझौते की वार्ता के कई स्तर होते हैं। वह एक ही साथ दो-तीन स्तरों पर चल सकती है। यह राज्य के अध्यक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से हो सकती है, इसे विदेश सचिव पत्र-व्यवहार द्वारा कर सकते हैं अथवा विदेश-मन्त्रियों का सम्मेलन किया जा सकता है। राजदूत भी इसके लिए उपयुक्त अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का स्थान (Place of Diplomacy in International Politics)

अभी तक के विवरण से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति के महत्व पर विभिन्न सन्दर्भों में प्रकाश डाला जा चुका है, तथापि मॉर्गेंथो ने 'कूटनीति के गुण' शीर्षक के अन्तर्गत जो विचार प्रकट किए हैं वे अपठनीय हैं¹ क्योंकि उनसे हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति के महत्व के सार का अच्छा बोध होता है। मॉर्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जो भी तत्त्व योग देते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व कूटनीति की उत्तमता है, भले ही यह तत्त्व कितना ही कम्यो न हो। राष्ट्रीय शक्ति को निश्चित करने वाले अन्य सभी तत्त्व तो वास्तव में वह कच्चा माल है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति गढ़ी जाती है। यह राष्ट्र की कूटनीति की उत्तमता ही है जो इन तत्वों को एक लड़ी में गुँथती है,

उन्हें दिशा और गुरुता प्रदान करती है तथा उनकी सुष्ण सम्भावनाओं को वास्तविक शक्ति की साँसें प्रदान कर जाग्रत करती है। किसी राष्ट्र के विदेशी मामलों का उसके कूटनीतिज्ञों द्वारा संचालन करना राष्ट्रीय शक्ति के लिए शान्ति के समय भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है जितना कि युद्ध के समय राष्ट्रीय शक्ति के लिए सैनिक नेतृत्व द्वारा व्यूह-रचना और दाब-नेचों का संचालन। यह वह कला है जिसके द्वारा राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों से स्पष्ट रूप से सम्बन्धित मामलों में अधिकधिक प्रभावी रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है।

मॉर्गेंथो ने कूटनीति को राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क (Brain of National Power) माना है और राष्ट्रीय मनोबल या हौंसले को उसकी आत्मा (National morale is its soul) की सजा दी है। यदि कूटनीति का दृष्टिकोण दूषित है, इसके निष्पत्ति गलत हैं तो अन्य तत्त्व अन्तर्गतत्वा एक राष्ट्र के लिए कम योगदान दे पाएँगे। कूटनीति में पिछड़ जाने पर एक देश अन्तर्गतत्वा अपने अन्य तत्वों के लाभों को भी खो बैठेगा और अपने अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रहेगा या बहुत दुर्बल सिद्ध होगा। मॉर्गेंथो का स्पष्ट मत है कि अन्त में ऐसे राष्ट्र को उस राष्ट्र के सम्मुख झुकना ही पड़ेगा जिसकी कूटनीति अपने अन्य राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का सम्पूर्ण प्रयोग करती है और इस तरह अन्य शक्तों की कमी की पूर्ति अपनी स्वयं की श्रेष्ठता से करने में सफल हो जाती है। अपने राष्ट्र की शक्ति-सम्भावनाओं का पूर्ण लाभकारी प्रयोग कर एक योग्य कूटनीति अपने राष्ट्र की शक्ति को उस सीमा से कहीं अधिक बढ़ा सकती है जितनी कि अन्य तत्वों के समन्वय के उपरान्त कोई आशा कर सकता है। मॉर्गेंथो के ही योजस्वी शब्दों में "इतिहास में प्रायः बुद्धि तथा आत्मा से रहित 'गोलियाय' 'डेबिड' द्वारा मारा गया है जिसके पास मस्तिष्क और आत्मा दोनों ही थे। उत्तम श्रेणी की कूटनीति विदेश-नीति के लक्ष्य तथा साधनों का राष्ट्रीय शक्ति के प्राप्य साधनों से सामञ्जस्य स्थापित कर देगी। वह राष्ट्रीय शक्ति के गुप्त स्रोतों की खोज कर लेगी और उन्हें स्थायी रूप से राजनीतिक सत्यताओं में परिणत कर देगी। राष्ट्रीय प्रयत्न को दिशा प्रदान कर वह अन्य तत्वों जैसे, भौगोलिक सम्भावनाओं, सैनिक तैयारी, राष्ट्रीय परिव्र तथा राष्ट्रीय हौंसले का प्रभाव बढ़ा देगी। यदि नीति के लक्ष्य तथा साधन स्पष्ट रूप से विदित हो तो राष्ट्रीय शक्ति अपनी समस्त सम्भावनाओं का पूरा सदुपयोग कर सामान्यतया किन्तु युद्ध के समय विशेष रूप से उच्चतम शिखर पर पहुँच सकती है।"

मॉर्गेंथो ने अपने विवरण में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् के उदाहरणों को प्रचुर मात्रा में देकर बताया है कि कूटनीति किस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का अत्यन्त शक्तिशाली तत्व है। दो महायुद्धों के बीच संयुक्तराज्य अमेरिका ने उस राष्ट्र का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया जो शक्तिशाली होने के बावजूद विश्व-मामलों

मे हल्की भूमिका अदा करता है। संयुक्तराज्य अमेरिका की विदेश-नीति इतनी शिथिल रही कि वह अपनी शक्ति के पूर्ण प्रभाव को अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर केन्द्रित नहीं कर सका। अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिज पर संयुक्तराज्य की शक्ति का घसर निराशाजनक प्रतीत हुआ क्योंकि अमेरिकी कूटनीति इस तरह संचालित हुई मानो अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के लाभ, उसके प्राकृतिक साधनों, उसकी भौद्योगिक सम्भावनाओं, जनसंख्या, गुण आदि तत्वों का अस्तित्व ही न हो। सन् 1890 से 1914 के मध्य का फ्रांस एक ऐसे राष्ट्र का उदाहरण है जो अन्य पक्षों में बुरी तरह पिछड़ गया हो लेकिन केवल शानदार कूटनीति (Brilliant Diplomacy) के बल पर शक्ति के उच्च शिखर पर पहुँच गया हो। सन् 1870 में जर्मनी के हाथों बुरी तरह पराजित होने के बाद फ्रांस एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति रह गया और बिस्मार्क की जादुई कूटनीति ने उसे यूरोप के राष्ट्रों से अलग-थलग कर बराबर द्वितीय श्रेणी की शक्ति ही बनी रहने दिया, लेकिन सन् 1890 में बिस्मार्क के पतन के बाद जर्मनी की विदेश-नीति रूस से दूर होने लगी, वह ग्रेट-ब्रिटेन की शकाओं के समाधान के लिए इच्छुक नहीं रही और जर्मन विदेश-नीति की इन झुटियों का फ्रांसीसी कूटनीति ने पूरा लाभ उठाया। सन् 1894 में फ्रांस ने रूस से किए गए सन् 1891 के राजनीतिक समझौते में सैनिक सन्धि को जोड़ दिया और सन् 1904 तथा 1912 में उसने ग्रेट-ब्रिटेन से औपचारिक समझौते किए। सन् 1914 में जहाँ फ्रांस ने एक समृद्ध मित्रराष्ट्र को अपने मददगार पाया वहाँ जर्मनी के एक मित्र इटली ने अपने मित्र को ही घोखा दे दिया और जर्मनी के अन्य मित्रों आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा टर्की आदि की कमजोरियाँ भी जर्मन पर भार बन गईं। मॉर्गेंथो के अनुसार यह कार्य फ्रांस के प्रतिभावान कूटनीतिज्ञों के माइल बंदे (इटली में फ्रांस का राजदूत), जल्सकैवोन (जर्मनी में फ्रांस का राजदूत), पोल कैंबोन (ब्रिटेन में फ्रांस का राजदूत), मोरिस पोसियो लीग (रूस में फ्रांस का राजदूत), आदि का था।

पुनश्च, दोनों विश्व-महायुद्धों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रुमानियों ने अपने साधनों की तुलना से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की थी, उसका मुख्य श्रेय एक व्यक्ति अर्थात् विदेश मंत्री हिटुलेस्वगु को था। इसी प्रकार इतने छोटे तथा अनिश्चित स्थिति में होने के बावजूद उन्नीसवीं शताब्दी में बेल्जियम ने जो शक्ति प्राप्त कर ली थी, वह उसके तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा चुरत राजा लिओपोल्ड प्रथम व लिओपोल्ड द्वितीय के व्यक्तित्व के कारण थी। सत्रहवीं शताब्दी में स्पेन की कूटनीति ने तथा उन्नीसवीं शताब्दी में तुर्किस्तान की कूटनीति ने उनके राष्ट्रीय क्षय की खाई को कुछ समय के लिए पाटे रखा था। ब्रिटिश शक्ति के उतार-चढ़ाव ब्रिटिश कूटनीति की उत्तमता के परिवर्तनों से जुड़े रहे हैं। कार्डिनल वून्जे, बसलरे तथा कनिंग ब्रिटिश कूटनीति के उच्चतम शिखर का प्रदर्शन करते हैं, जबकि लॉर्ड नार्थ तथा नेवाइल चैम्बरलेन दोनों ह्रास के द्योतक हैं। रिचर्ड मजारीन अथवा तेल्लरों की कूटनीति के बिना फ्रांस की शक्ति क्या होती? बिना बिस्मार्क के जर्मनी की शक्ति क्या होती? बिना कैसर के इटली की शक्ति क्या होती? इसी तरह नवीन

अमेरिकी गणतन्त्र अपनी शक्ति के लिए क्या प्राकलित, जेकरसन, मेडीसन, जेय तथा एडम्स के प्रति ऋणी नहीं हैं जो उसके राजदूत व राज्य-सचिव थे ? और भी उदाहरण हैं तो सन् 1890 में बिस्मार्क के राजनीतिक मंच से हट जाने के उपरान्त जर्मन कूटनीति के गुणों में गम्भीर तथा स्वाधी गिरावट आ गई। फलस्वरूप जर्मनी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की क्षति का अन्त उस सैनिक परिस्थिति में हुआ जिसका सामना उसे प्रथम विश्व-महायुद्ध में करना पड़ा। हिटलर के मामले में जर्मनी की कूटनीति की दृढ़ता फ्युर्रर के मस्तिष्क में निहित थी। सन् 1933 से 1940 तक जो जर्मन कूटनीति की विजय एक व्यक्ति के मस्तिष्क की विजय का परिणाम थी और उस मस्तिष्क के क्षय के कारण ही नाजी शासन के अन्तिम वर्षों में उसे विध्वंसकारी दुर्घटनाओं को सहन करना पड़ा था।

मार्गेन्यो का मत है कि राष्ट्रों को अपनी कूटनीति पर उन विभिन्न तत्त्वों के उत्प्रेरक के रूप में अवलम्बित रहना चाहिए जो कि राष्ट्र की शक्ति के अंग होते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार भी ये विभिन्न-तत्त्व कूटनीति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर हावी कराए जाते हैं, वही उस क्षेत्र में राष्ट्रीय शक्ति का रूप होता है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वैदेशिक कूटनीतिक संगठन सदा उत्तम अवस्था में रहे। स्वाधी श्रेष्ठता परम्पराओं पर अवलम्बित होकर ही सर्वोत्तम रूप में हासिल की जा सकती है न कि कभी-कभी अति-गुणल व्यक्तियों के सम्मुख आ जाने से।

स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का महत्त्व सुदूर प्रतीत से रहा है और आधुनिक युग में तो यह अत्यधिक बढ़ गया है। एक भूतपूर्व अमेरिकी राजदूत लियो बी. पौलाद (Leon B. Poullada) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का स्थान इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कूटनीति का अधिक अध्ययन, (1) शक्ति और प्रभाव के अध्ययन को (Studies of Power and Influence), (2) महत्त्वपूर्ण अन्तःक्रियाओं के अध्ययन को (Studies of Strategic Interactions), (3) सौदेबाजी और समझौता-वार्ता सम्बन्धी अध्ययनों को (Studies of Bargaining and Negotiations), एवं (4) निर्णय करने सम्बन्धी अध्ययनों को (Studies of Decision-Making) सुधारता है।¹

कूटनीति के विभिन्न प्रकार

(Different Kinds of Diplomacy)

कूटनीति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, किस विधि से किया जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका क्या स्वरूप है तथा उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आदि महत्त्वपूर्ण बातों के अन्तर के कारण कूटनीति को अनेक रूपों में विभाजित किया जाता है, जैसे—

(1) प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति (Democratic Diplomacy)

1 David S. Mclellan, William C. Olson, Fred A. Sandermann : The Theory and Practice of International Relations, 1974 (Article by Leon B. Poullada), p. 199.

- (2) सर्वाधिकारवादी कूटनीति (Totalitarian Diplomacy)
- (3) सम्मेलनों की कूटनीति (Diplomacy by Conferences)
- (4) व्यक्तिगत (प्रतिनिधि द्वारा) कूटनीति (Personal Diplomacy)
- (5) गुप्त कूटनीति (Secret Diplomacy)
Vs. खुली कूटनीति (Open Diplomacy)
- (6) दूकानदार जैसी कूटनीति (Shopkeeper Diplomacy)
Vs. युद्धप्रिय कूटनीति (Warrior Diplomacy)
- (7) प्रचार की कूटनीति (Propaganda Diplomacy)

कूटनीति के विभिन्न रूपों में परस्पर कोई सम्बन्ध न हो, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि इनमें से कुछ तो एक दूसरे की विरोधी प्रकृति की हैं फिर भी यह सम्भव है कि एक देश की कूटनीति में इनमें से कुछ रूप एक साथ प्राप्त हो सकें। उदाहरण के लिए एक कूटनीति प्रजातन्त्रात्मक होने के साथ-साथ प्रचार की, खुले सम्मेलनों की एवं दूकानदार जैसी भी हो सकती है। इस दृष्टि से यदि कूटनीति के उपर्युक्त विभिन्न अन्तरो को 'अन्तर' की सजा न देकर केवल कूटनीति की विशेषताएँ बड़े तो भी अनुचित न होगा।

1. प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति (Democratic Diplomacy)—बीसवीं शताब्दी को 'प्रजातन्त्र' के जन्म एवं विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय शासनसत्ता राजा और सम्राटों के हाथ से निकल कर सामान्य जनता के हाथों में आ गई। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का निर्णायक एक देश का शासक मात्र न रह कर पूरी जनता बन गई। प्रजातन्त्रात्मक प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ने कूटनीतिक व्यवहार पर प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया। कूटनीतिज्ञ अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी बन गए, किन्तु जैसा कि पामर तथा पकिंस का विचार है, कूटनीतिक कार्यों पर आज भी उन्हीं लोगों का अधिकार है जिनके हाथ में शक्ति, प्रभाव और धन है। प्राचीन भारत के अनेक राजा, महाराजा और जागीरदार स्वतन्त्र भारत के राजदूतों का पद सम्भाले हुए हैं।

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति की कुछ विशेषताएँ हैं जैसे—

1. कूटनीतिज्ञों को केवल अपने देश के शासकों की रचि का ध्यान रखना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें लोक-रचि और लोकहित का भी ध्यान रखना होता है।
2. कूटनीतिक स्तर पर किए गए सन्धि एवं समझौतों से सामान्य जनता को परिचित रखना आवश्यक है ताकि जनता उन पर अपना मत व्यक्त कर सके।
3. जनता के अनेक समुदाय एवं समस्याएँ भाषण, प्रचार, आन्दोलन एवं जुलूसों द्वारा विदेशों से किए गए सन्धि या समझौतों का विरोध या समर्थन कर सकते हैं।
4. प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति एक देश की स्वतन्त्र प्रेस, भाषण की स्वतन्त्रता सरकारी अधिकारियों पर जनमत का प्रभाव, विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के विशेष हितों आदि के साँच्चों के ढलने के बाद रूप ग्रहण करती है तथा कूटनीति के इस रूप का लक्ष्य होता है—सम्पूर्ण देश का सामान्य हित।

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति के अब तक के अनुभव अधिक अच्छे नहीं हैं। निकल्मन ने अपनी पुस्तक 'कूटनीति' (Diplomacy) के पाँचवें अध्याय में प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति के अनेक दोषों का वर्णन किया है। प्रथम दोष यह है कि इसमें 'मन्त्रमुं जनता' अनुत्तरदायी होती है। कूटनीतिक कार्यों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालना जनता का अधिकार समझा जाता है, किन्तु उन कार्यों से होने वाले दुष्परिणामों के लिए वह जिम्मेदार नहीं बनना चाहती।

दूसरा दोष यह है कि सामान्य नागरिक विदेश-नीति से सम्बन्धित निर्णय लेने में अक्षम रहता है। यदि उसके सम्मुख सभी तथ्य यथाविधि प्रस्तुत कर दिए जाएँ तो भी वह अपने मस्तिष्क पर विश्व-राजनीति का सन्तोषजनक चित्र नहीं उतार सकता और न ही वह उसके आगामी परिणामों का अनुमान लगा सकता है।

तीसरा दोष यह है कि आंशिक रूप से सूचित लोग विदेश-नीति के उनमें हुए प्रश्नों पर शीघ्रतापूर्वक विधायी (Positive) निर्णय ले लेते हैं। इससे उन लोगों के लिए एक दुःख स्थिति पैदा हो जाती है जो तथ्यों के आधार पर कुछ बौद्धिक निर्णय लेना चाहते हैं।

चौथा दोष यह है कि प्रजातन्त्र में लोकमन द्वारा एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है जिसके आधार पर एक देश की विदेश-नीति संचालित होनी चाहिए। इस सीमा के अनेक लाभ हैं, साथ ही सबसे बड़ा दोष यह है कि देश के नेता अवसर के अनुकूल कोई निर्णय तत्काल नहीं ले पाते। पामर तथा पॉक्स के कथनानुसार प्रजातन्त्रीय देशों द्वारा 'बहुत कम और बहुत देर की नीति' (Too Little and Too Late) अपनाने के लिए उनकी आलोचना की जाती है। समय पर कोई कदम न उठाने के बाद में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

पाँचवाँ दोष यह है कि कथनी और करनी के बीच भारी अन्तर रहने लगा है। वार्तालाप, भाषण एवं कार्यों द्वारा मही प्रयास किया जाता है कि नीति का वास्तविक स्वरूप लोगों की आँखों से ओभल रहे।

2. सर्वाधिकारवादी कूटनीति (Totalitarian Diplomacy)—बीसवीं शताब्दी का ही एक दूसरा विकास सर्वाधिकारवाद है। इस व्यवस्था में देश की कूटनीति के संचालक उच्च स्तर के कुछ गणमान्य नेता होते हैं। प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से ये लोग देश में अपनी महत्वाकांक्षाओं एवं सही लक्ष्यों को पढ़े के पीछे डाल देते हैं। सर्वाधिकारी राज्यों के आदर्श, विश्वास, लक्ष्य एवं कार्य भिन्न होने के कारण उनकी कूटनीति का रूप भी प्रजातन्त्रात्मक देशों से भिन्न रहता है। इस कूटनीति की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

1. यह कूटनीति विचारधारा (Ideology) को आधार बना कर आगे बढ़ती है तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जातीय गौरव, भौतिकवाद, सैनिकवाद आदि का सहारा लेती है।

2. सर्वाधिकारी कूटनीतियों का मूल उद्देश्य शान्तिपूर्ण अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का निर्माण करना न होकर अपनी विचारधारा का प्रसार करना है। इसके लिए दूसरे देशों में वे विशेष दलों का निर्माण, पोषण एवं समर्थन करते हैं।

3. सर्वाधिकारी कूटनीतिज्ञ कूटनीति के सामान्य नियमों का पालन तभी तक करते हैं जब तक वह उनके स्वामियों की योजनाओं से मेल खाता हो।

4. उनके मतानुसार किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि एवं समझौते को इच्छानुसार तोड़ा या अस्वीकृत किया जा सकता है।

5. ये कूटनीतिज्ञ प्रचार करते हैं कि साम्यवादी एवं पूंजीवादी राज्यों के बीच संघर्ष एवं मतभेद स्थायी हैं।

6. सर्वाधिकारी राज्यों के साथ अन्य राज्यों के सम्बन्ध प्रायः बड़े भेदपूर्ण एवं संघर्षपूर्ण होते हैं—कभी-कभी तो इतने कि कूटनीति का व्यवहार तक असम्भव बन जाता है। शीतयुद्ध समाप्त होने के साथ-साथ अब दोनों पक्षों के बीच समझौते की माथा बढ़ती जा रही है।

3. सम्मेलनों की कूटनीति (Diplomacy by Conference)—कूटनीति के रूप में प्रथम विश्व-युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस काल में लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना की गई। इससे विश्व के राष्ट्रों को मिल कर तथा सम्मेलनों में विचार-विमर्श से अपनी समस्याओं को सुलझाने की प्रेरणा मिली। समय के अनुसार यह विचार व्यवहार में लोकप्रिय बनता चला गया और द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद सम्मेलनों के माध्यम से कूटनीतिक व्यवहारों को संचालित करना एक साधारण बात हो गई।

सम्मेलन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वे सम्मेलन जो महत्वपूर्ण तथा तकनीकी मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं। ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थोड़ी होती है; केवल विशेषज्ञ ही भाग लेते हैं। दूसरे प्रकार के वे सामान्य सम्मेलन होते हैं जिनमें सैकड़ों व्यक्ति भाग लेते हैं। ऐसे सम्मेलन प्रायः संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्वधान में आयोजित किए जाते हैं तथा उच्च स्तर के कूटनीतिज्ञ भी इनमें भाग लेते हैं।

लाइड जॉर्ज के युद्ध-मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य मॉरिस हंके (Lord Maurice Hankey) ने 'सम्मेलन की कूटनीति' को युद्ध रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना है। उनके अनुसार ऐसी कूटनीति के अनेक लाभ हैं जैसे—इसकी प्रक्रिया सचीनी होती है, अनौपचारिकता रहती है, सदस्य एक दूसरे से परिचित रहते हैं, निष्ठान्तों के बीच भंगी रहती है, गुप्त प्रक्रियाओं एवं प्रकाशित परिणामों के बीच सामंजस्य रहता है, सचिव एवं व्याख्याता विश्वमनीय होते हैं।¹

अनेक क्षेत्रीय तथा अन्य प्रकार के समूह जैसे नाटो (NATO), अमेरिकी राज्यों का संगठन (OAS) तथा योरोपीय एकता आन्दोलन आदि को भी सम्मेलन की कूटनीति के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इन मीमिन समूहों के बीच समझौते की वार्ता कभी-कभी पर्याप्त कठिन हो जाती है क्योंकि इन देशों का सम्बन्ध पर्याप्त निकट का है। पेडलफोर्ड तथा लिबन के मतानुसार राजनीतिक विपक्षियों एवं

विरोधियों की अपेक्षा कई बार मित्रों के साथ खेल-देन की बात करना अधिक बटिन होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जब से जनता रुचि लेने लगी है, तब से सम्मेलन की कूटनीति अधिक लोकप्रिय बन गई है। अब महाशक्तियाँ छोटे राज्यों की भावाज को महत्व देने लगी हैं और इनके समर्थन की आवश्यकता महसूस करने लगी हैं। अतः एक समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि जब बड़े राज्य कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो छोटी शक्तियाँ माँग कर सकती हैं कि किसी राज्य की शालोचना या गिन्दा करने से पूर्व उस पर मतदान करा लिया जाए। यह माँग बड़ी शक्तियों को कितनी ही बार बड़ी परेशानी में डाल देती है क्योंकि वे छोटे राज्यों पर आक्रमण करने की इच्छा को पूरी नहीं कर पाती। इसीलिए वे कभी-कभी इस प्रकार के मतदान की उपयुक्तता के बारे में सन्देह प्रकट करती हैं। सम्मेलन की कूटनीति, संयुक्त नियोजन एवं क्रिया का प्रयोग करके विशेष क्षेत्रों के बीच सहयोग में वृद्धि करती हैं। उदाहरण के लिए, नाटो को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसने शान्तिकालीन सैनिक सहयोग का विकास किया है।

सम्मेलन की कूटनीति का एक दूसरा विकास समाज की मान्यता का विकास है। यह यूरोपीय आर्थिक समाज तथा इससे सम्बद्ध निकायों की रचना द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। सम्मेलन की कूटनीति ने ही संसदीय कूटनीति को जन्म दिया है जो आज के कूटनीतिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

सम्मेलन की कूटनीति हमेशा खुली कूटनीति होती है। जिस प्रकार खुले समझौते खुले में किए जाते हैं उसी प्रकार खुले मतभेद भी खुले में ही प्रदर्शित किए जाते हैं। इससे यह सम्भावना रहती है कि सम्बन्धित दोनों पक्षों के हितों का नुकसान हो और उस सम्मेलन या संगठन का नुकसान हो जिसमें बिं ये किए गए हैं। कभी-कभी वाद-विवाद और असहमति को जनता की आँखों से प्रोभल रखना अच्छा समझा जाता है क्योंकि इससे समस्या स्पष्ट होती है और विवादपूर्ण समस्याओं पर विचार-विमर्श अच्छी तरह किया जा सकता है। सम्मेलन की कूटनीति को कभी-कभी प्रचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रवृत्ति खतरनाक है क्योंकि इससे हर देश अपनी शक्ति बढ़ाने और अन्य की शक्ति को कम करने का प्रयास करता है।

सम्मेलन की कूटनीति की अनेक सीमाएँ हैं। कूटनीति के इस रूप का समर्थन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया दिखाई देती है जैसी किसी राज्य की व्यवस्थापिका के अधिवेशन में रहती है। किन्तु असल में किसी व्यवस्थापिका के अधिवेशन तथा सम्प्रभु राज्यों के सम्मेलनों में पर्याप्त अन्तर रहता है। दूसरे, इन राज्यों के प्रतिनिधि स्वतन्त्र एजेंट नहीं होते, अपितु अपनी सरकारों के निर्देशनों से बंधे रहते हैं और उनका काम होता है कि वे अपने राज्य के हितों की रक्षा एवं अभिवृद्धि करें।

साम्यवादी राज्यों एवं पश्चिमी शक्तियों के बीच सम्मेलन की कूटनीति के विषय कुछ बातों पर गिन्न राष्ट्यों के बीच समझौता होगा जरूरी है कि किस विषय

पर समझौता-वार्ता की जाए ? कब की जाए ? क्या समझौते' तथा मुक्तिपत्रों की जा सकती हैं और कब कड़ा दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है ? जो भी महत्त्वपूर्ण समझौते किए जाएं वे सम्बन्धित सरकार द्वारा स्वीकृत होने चाहिए । कुछ स्थितियों में महत्त्वपूर्ण समझौते देश की व्यवस्थापिकाओं के सम्मुख स्पष्ट करने होते हैं क्योंकि उनकी स्वीकृति परमावश्यक है । जेम्स रेस्टन (James Reston) का कहना है कि समझौतों को करते समय प्रेस पर भी दृष्टि रखनी होती है क्योंकि प्रजातन्त्र में प्रेस पर्याप्त साधनसम्पन्न होता है और वह यह मान कर कार्य करता है कि सभी कूटनीतिक प्रयास समाचार होते हैं ।

सर्वाधिकारवादी राज्यों के अधिकारियों को राजनीतिक स्थिति एवं प्रेस के इतने दबावों के अधीन कार्य नहीं करना होता । ये देश समझौतों को किसी भी समय बिना निस्संकोच बदल सकते हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ का प्रेस भी उपयुक्त सत्ता की स्वीकृति प्राप्त किए बिना सम्मेलन के वार्तालाप को प्रकाशित नहीं करता । इसके अतिरिक्त प्रेस निर्णय लेने वालों के मध्य स्थित विवादों को भी प्रकाशित नहीं करती और न ही यह प्रकाशित करती है कि निर्णयकों द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए किस प्रकार प्रयास किया गया, क्योंकि यह समझा जाता है कि ऐसा करने से विरोधियों को बल मिलेगा ।

4. व्यक्तिगत कूटनीति (Personal Diplomacy) — कूटनीति के इस रूप के अनुसार दो देशों के कूटनीतिक विषयों का संचालन स्वयं उन देशों के विदेश मन्त्रियों, प्रधानों एवं प्रमुखों द्वारा किया जाता है, न कि उनके कुछ प्रतिनिधियों द्वारा । कूटनीति के इस रूप का प्रयोग पहले की होता था, किन्तु वर्तमान युग में तो यह एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है । अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर इन उत्तमदायी व्यक्तियों द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं । जेनेवा सम्मेलन, वाण्डुंग सम्मेलन, अल्जीरिया सम्मेलन एवं अन्य अनेक शिखर-सम्मेलनों को इस प्रकार की कूटनीति के उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है । द्वितीय विश्वयुद्ध-काल में एवं उसके बाद भी बड़ी शक्तियों के विदेश-मन्त्री अनेक महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करने को मिले हैं । शीतयुद्ध-काल में नाटो (NATO) शक्तियों के विदेश-मन्त्री अपने सामान्य हित के मामलों पर विचार करने के लिए कई बार मिल चुके हैं ।

व्यक्तिगत कूटनीति को क्रियान्वित करने के लिए कई बार एक देश के प्रधानमन्त्री एवं विदेश मन्त्रियों द्वारा प्रतिनिधियों की सहायता ली जाती है । स्वयं के कार्य को हल्का करने एवं कार्य की सम्पन्नता में समय की बचत करने के लिए ऐसा किया जाता है । भारत-पाक संघर्ष के समय भारत ने अनेक मन्त्रियों एवं महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को कार्यकारिणी के एजेंट भ्रमण प्रधानमन्त्री के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में भेजा था; क्योंकि इस संघर्ष में भारत के पक्ष को स्पष्ट करना तथा दूसरे देशों की सहानुभूति एवं सहयोग शीघ्र ही प्राप्त करना आवश्यक था । ताशकन्द में शास्त्री-अपूर्व मेट और मन् 1971 में शिमला में इन्दिरा-भुट्टो मेट व्यक्तिगत कूटनीति का ही एक रूप कहा जा सकता है । द्वितीय विश्वयुद्ध के अभिनेता चर्चिल और रुजवेल्ट प्रायः धनीस्वार्थिक एवं व्यक्तिगत रूप से ही मिला करते थे ।

कुछ विचारकों के मतानुसार व्यक्तिगत कूटनीति हानिकारक है। प्रधान-मन्त्री, विदेशमन्त्री आदि उच्च स्तर के नेताओं का काम नीति का निर्माण करना है न कि समझौते करना, यह काम तो कूटनीतिक विशेषज्ञों को सौंप देना चाहिए। कारण यह है कि उच्च स्तर के अधिकारी समझौते करने के लिए योग्य नहीं होते। साथ ही यह डर रहता है कि वे विषय को व्यक्तिपरक (Subjective) दृष्टि से देखेंगे जो राष्ट्रीय हित के विपरीत भी जा सकता है। गलांड वंसटार्ट (Lord Vansittart) के मत में ऐसी कूटनीति का उपयोग कभी-कभी ही सफल हो पाता है क्योंकि 'परामर्श' की प्रत्येक को आवश्यकता रहती है। हेराल्ड निकल्सन (Harold Nicolson) तथा सिसली हडल्स्टन (Ssley Huddleston) आदि का विचार भी व्यक्तिगत कूटनीति के विरुद्ध है।

दूसरी ओर लॉर्ड हेकी (Lord Hankey) आदि के विचार से व्यक्तिगत कूटनीति का अपना महत्व है क्योंकि कई समस्याओं का समाधान इतना कठिन हो सकता है कि कूटनीतिज्ञों के पास जो साधन हैं वे उसके लिए अपर्याप्त रह जाएँ। इन विचारकों के मत में संसदारीय प्रजातन्त्र के युग में मध्यस्थों पर निर्भर रहना उपयुक्त नहीं है।

5. दूकानदार जैसी कूटनीति बनाम युद्धप्रिय कूटनीति (Shopkeeper Diplomacy Vs. Warrior Diplomacy)—यदि हम विभिन्न देशों की कूटनीति पर दृष्टि डालें तो विदित होगा कि उन सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। निकल्सन (Nicolson) ने ग्रेट ब्रिटेन की कूटनीति में वे सभी गुण पाए हैं जो किसी व्यापार में पाए जाते हैं।¹ जो कूटनीति बुद्धिपूर्ण समझौते करने को तैयार रहती है, दूसरे राष्ट्रों के साथ प्रेम बढाती है तथा विभिन्न सन्धियों द्वारा शान्ति-निर्माण में प्रयत्नशील रहती है, वही कूटनीति व्यवहार में वाञ्छित परिणामों को प्राप्त कर पाती है। एक दूकानदार जैसी यह कूटनीति महत्वपूर्ण एवं लाभदायक होती है क्योंकि यह अन्य रूपों की अपेक्षा अधिक नैतिक है तथा उन रूपों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त करने में समर्थ रहती है। एक देश की सफलता एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाज में उसका स्थान मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है—वह देश किस प्रकार की कूटनीति अपना रहा है, उस देश की राष्ट्रीय नींव कैसी है, तथा समझौता-कर्ताओं का व्यक्तित्व कैसा है।

कूटनीति का एक दूसरा युद्धप्रिय रूप है। इसका समझौतों में विश्वास नहीं होता वरन् यह युद्ध के वातावरण को अधिकाधिक उत्तेजित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार की कूटनीति को मानने वाला देश अन्त में स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

दूकानदार जैसी एवं युद्धप्रिय कूटनीतियों के बीच अनेक भिन्नताएँ हैं। दोनों ही विशेषताएँ परस्पर विरोधी हैं। जो देश की व्यवस्था को यथास्थिति में रखने के

पक्ष में हैं। वे पहली को दूकानदार जैसी कूटनीति को अपनाते हैं और जो देश की यथास्थिति को चुनौतियाँ देते हैं तथा बदलने की कोशिश में रहते हैं वे युद्धप्रिय नीति को अपनाते हैं। पश्चिमी प्रजातन्त्रों में दूकानदार जैसी कूटनीति की सभी विशेषताएँ वर्तमान हैं। दूसरी ओर साम्यवादी देशों की कूटनीति में युद्धप्रियता का आभास मिलता है—विशेषतः साम्यवादी चीन की कूटनीति में।

दोनों ही प्रकार की कूटनीतियों का आधार परिस्थितियाँ, राज्य का स्वरूप एवं विचारधारा है, अतः दोनों का ही अपना महत्त्व है। दूकानदार जैसी कूटनीति को क्रियान्वित करते समय ब्रिटेन ने कई बार चातुर्य, कुशलता एवं कपट से काम लिया है। इसमें उसे सफलता भी मिली है और असफलता भी। एक देश कूटनीति के किस रूप को अपनाता है तथा उस रूप को अपनाने में उसे कितनी सफलता प्राप्त होती है, इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह देश कौन-सा स्थान रखता है और उस देश की शक्ति कितनी है। प्रारम्भ में ब्रिटेन की कूटनीति सफल रही थी इसका कारण उसकी शक्ति थी। मिस्र के मामले में उसे पीछे हटना पड़ा; इसका कारण यह था कि अब वह दूसरी श्रेणी की शक्ति रह गया है।

युद्धप्रिय तथा दूकानदार जैसी कूटनीतियों के बीच का मुख्य अन्तर इस प्रकार है—

1. युद्धप्रिय कूटनीति जब समझौते करने बैठती है तो अविवेकपूर्ण (Unreasonable) बन जाती है क्योंकि विवेक से सोचने पर यथास्थित-व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। इसके विपरीत दूकानदार जैसी कूटनीति बुद्धिपूर्ण समझौते करती है।

2. प्रभावशाली (Dominant) देशों की माँग थोड़ी तथा बुद्धिपूर्ण होती है। वे यथास्थित-व्यवस्था से सन्तुष्ट रहते हैं और इसलिए शक्ति के प्रयोग के प्रत्येक रूप को बुरा समझते रहते हैं और समझौतों को आवश्यक मानते हैं। इसके विपरीत चीन जैसे देश युद्ध को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का आवश्यक साधन मानते हैं।

3. प्रभावशाली देशों की (जो यथास्थित-व्यवस्था के पक्षधर हैं) कूटनीति स्पष्ट रहती है। उनके कूटनीतिक समझौतों का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता।

4. प्रभावशाली देश ऐसी किसी चीज की माँग नहीं करने जो उनके पास नहीं है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि दूसरे देश भी उन चीजों की माँग न करें जो उनके पास नहीं हैं। ये देश स्थित विश्व-व्यवस्था से सन्तुष्ट रहते हैं, अतः स्पष्टतः नहीं जान पाते कि उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं?

5. युद्धप्रिय कूटनीति को अपनाने वाले देशों के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं। वे वर्तमान को बदल कर अपने अनुकूल विश्व का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ उनके हितों को सन्तुष्ट किया जा सके। इस नए विश्व का मानचित्र उनके मस्तिष्क में रहता है। जैसे, साम्यवादी चीन सारे संसार को लाल भण्डे के नीचे लाने का स्वप्न देख रहा है।

6. पुद्बिप्रिय कूटनीति अपनाने वाले देश प्रायः गरीब, दुर्बल तथा असन्तुष्ट होते हैं। शक्ति के अभाव में उनको कूटनीतिक सफलताएँ कम मिल पाती हैं, विश्व-समाज में भी उनका स्तर अधिक ऊँचा नहीं उठता। यही कारण है कि वे वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए युद्ध और संघर्ष का सहारा लेते हैं, अविश्वेकपूर्ण समझौतों द्वारा आगे बढ़ते हैं। इकानधार जैसी कूटनीति अपनाने वालों का स्वभाव व लक्ष्य इसके विपरीत होता है।

6. खुली कूटनीति बनाम गुप्त कूटनीति (Open Diplomacy Vs. Secret Diplomacy)—प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति का वर्णन करते समय प्रसंगवश यह बताया गया था कि आज के प्रजातन्त्रात्मक युग में जनसाधारण अपना यह अधिकार मानने लगे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सन्धियाँ, समझौते अथवा कूटनीतिक व्यवहार हों उन सबकी जानकारी उनको दी जानी चाहिए। खुली कूटनीति का समर्थन नैतिक एवं आदर्शात्मक दृष्टिकोणों से भी किया जाता है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इस प्रकार की कूटनीति की माँग बढ़ी थी। वुडरो विल्सन के 14 सिद्धान्तों में से पहला सिद्धान्त था कि सभी शान्तिपूर्ण समझौते खुले रूप में किए जाने चाहिए। कूटनीति हमेशा जनता के दृष्टिकोण से एवं स्पष्ट रूप में संचालित की जाए न कि व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के आधार पर।¹ खुली कूटनीति के समर्थक अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं—

1. एक राष्ट्र के लोगों को यह अधिकार है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए समझौतों को जानें क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर घन और जीवन का बलिदान वे ही करते हैं।

2. प्रजातन्त्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यह उत्तरदायित्व तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि जनता को तथ्यों से परिचित न रखा जाए।

3. कूटनीतियों द्वारा जिन विध्वंसकारी युद्धों का वातावरण तैयार किया जाता है तथा जिसमें लोगों को जबरदस्ती भौक दिया जाता है, वह सब न हो यदि जनता का कूटनीतिक कार्यों पर संरक्षण रहे।

4. खुली कूटनीति का अर्थ, जैसा कि स्वयं विल्सन ने सीनेट को लिखा था, यह कदापि नहीं है कि महत्वपूर्ण मामलों पर व्यक्तिगत रूप से विचार-विमर्श ही न किया जाए। इसका अर्थ तो यह है कि कोई समझौता गुप्त न रखा जाए, तय करने के बाद सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्पष्ट कर देने चाहिए और प्रकाशित कर देने चाहिए।

उन तर्कों का विरोध करते हुए गुप्त कूटनीति के समर्थक अपने पक्ष में निम्नलिखित मुख्य तर्क प्रस्तुत करते हैं—

1. एक सफल कूटनीति के लिए गोपनीयता आवश्यक है।

1 Woodrow Wilson : Message to Congress on Jan. 8th, 1913.

2. गुप्त रूप से जो समझौते किए जाते हैं उनमें स्पष्टता (Frankness) रहती है तथा कूटनीतिज्ञ उन सुविधाओं को देने के लिए भी राजी हो जाते हैं जिनको वे तब नहीं दे सकते जबकि जनता उनसे परिचिन हो।

3. प्रकाशन की परम्परा से 'कूटनीतिज्ञ' प्रचारक (Propagandists) बन जाएंगे तथा वे जनता के क्षणिक दुराग्रहों से भी प्रभावित किए जाएंगे।

दोनों ही पक्षों के तर्कपूर्ण सन्तोषजनक नहीं हैं। खुली कूटनीति के समर्थकों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि कूटनीति को प्रजातन्त्रात्मक बनाने से युद्ध का खतरा टल जाएगा तथा शान्ति की जड़ें गहरी होगी, किन्तु यह मत दीखने में जितना सही लगता है, व्यवहार में हवाई किले से अधिक नहीं है।

गुप्त कूटनीति के समर्थकों का मुख्य विश्वास यह है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रकाशित कर दिया गया तो इससे समझौता करने वालों में सचीलापन नहीं रह पाएगा। वर्तमान समय के अधिकांश सम्मेलनों में समझौता करने वालों में सचीलापन नहीं रहता। इसका कारण यही माना जाता है कि उनको प्रकाशित कर दिया जाता है किन्तु यह विश्वास भ्रामक है। गुप्त कूटनीति के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि आज खुली कूटनीति असफल हो गई है। पहले कूटनीति सफल थी क्योंकि वह गुप्त होती थी। यह तर्क भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि कूटनीति की असफलता के अन्य दूसरे कारण बहुत हैं।

प्रजातन्त्रात्मक होने के लिए कूटनीति का खुला होना न आवश्यक है और न उपयोगी ही। पामर तथा पकिंस के विचार से जनता का भला इसमें है कि समझौतों के परिणामों एवं उद्देश्यों के लिए नेताओं को उत्तरदायी ठहराया जाए, न कि इसमें कि समझौते ही टेलीविजन के पर्दे पर किए जाएं।¹

7. प्रचार की कूटनीति (Diplomacy by Propaganda)—कूटनीतिक निर्णयों को अपने हितों के अनुकूल बनाने में प्रचार का महत्वपूर्ण योग है। रेडियो, प्रेस तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा जनता को एक विशेष नीति के सम्बन्ध में प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। जॉर्ज वी एलेन (George V. Allen) के मतानुसार प्रचार कूटनीतिक का एक सचेतन (Conscious) हथियार बन गया है। बिस्मार्क द्वारा इस हथियार का प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक किया जाता था। ब्रेस्ट लिटोवस्क (Brest Litovsk) में ट्रॉट्स्की ने भी समझौते के तरीके के रूप में प्रचार का प्रयोग किया था। बाद में यह व्यवस्था साधारण बन गई तथा अनेक देश इसे अपनाते लगे। कूटनीति में प्रचार दो प्रकार से सहायक बनता है—

1. प्रचार द्वारा समझौते पर पर विचार करने योग्य वातावरण तैयार किया जाता है।
2. जब समझौता हो रहा हो तो उसे प्रभावित करके अपने हित के अनुकूल बनाया जाता है।

जहाँ तक पहले कार्य का सम्बन्ध है, प्रचार उपयोगी है और इसलिए प्रत्येक देश प्रकाशन एवं प्रचार पर बहुत धन खर्च करता है किन्तु दूसरे कार्य का जहाँ तक सम्बन्ध है प्रचार बहुत कम ही सकल हो पाता है। प्रचार-कार्य मुख्य रूप से विदेश-मन्त्री या अन्य राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है, न कि कूटनीतिज्ञों द्वारा। यद्यपि प्रचार के द्वारा जनता में अनेक मिथ्या विश्वास एवं भ्रम पैदा होते हैं, किन्तु राज की परिस्थितियों में यह अपरिहार्य बन गया है। पत्रिकार ने समझौते (Negotiation) को एक गुप्त प्रणाली माना है। उनके मतानुसार जिस समय समझौते चल रहे हो उस समय प्रचार बड़ा खतरनाक होता है।¹

प्रचार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कूटनीति को कियान्वित किया जाता है। पामर तथा पकिस के कथनानुसार, "कूटनीति में प्रचार के समस्त साधनों का पूरा प्रयोग सर्वाधिकारवादी राज्यों में किया जाता है।" मास्को तथा पीकिंग आदि द्वारा यह साधन पूरी शक्ति से अपनाया जाता है। कूटनीति के व्यवहार पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसको अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे एक उच्च स्थान प्रदान किया है। युद्ध के समय प्रचार का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। शान्ति और संधि प्रत्येक अवस्था में प्रचार का अपना उपयोग है।

कूटनीति पर प्रभाव डालने वाले कुछ नए विकास (New Developments Responsible for Changing Role of Diplomacy)

आज कूटनीति द्वारा विश्व राजनीति में उस कार्य का सम्पादन नहीं किया जा रहा है जो विश्व-युद्धों के पूर्व होता था। मॉर्गन्थो (Morgenthau) के मतानुसार, "द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद कूटनीति अपना महत्त्व खो चुकी है। इसके कार्य अब जितने कम रह गए हैं उतने राज्य-व्यवस्था के इतिहास में कभी नहीं रहे थे।" कूटनीति का महत्त्व घटाने के लिए उन्होंने पाँच कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। ये निम्न प्रकार हैं—

1. संचार-साधनों का विकास (Development of Communications)
2. कूटनीति का घबमूल्यन (Depreciation of Diplomacy)
3. संसदात्मक प्रक्रिया द्वारा कूटनीति (Diplomacy by Parliamentary Procedure)
4. सर्वोच्च-शक्तियाँ—कूटनीति में नवगन्तुक (The Super Powers — Newcomers in Diplomacy)
5. वर्तमान विश्व-राजनीति का स्वरूप (The Nature of Contemporary World Politics)।

उपरोक्त कारणों से कूटनीति का व्यवहार कठिन बन गया है। विचारधारा के आधार पर संगठन के दो गुटों में बँट जाने से सबसे बड़ा खतरा कूटनीति को ही

हुआ है। कूटनीतिक व्यवहार केवल वही सम्भव होता है जहाँ इसकी इच्छाओं के बीच कुछ बातों में समानता हो। समझौते का प्रश्न भी वही उठता है जहाँ कुछ बातों में दोनों पक्ष सहमत हो तथा कुछ बातों पर उनमें मतभेद हो। समझौते द्वारा इस मतभेद को मिटाने का प्रयास होता है, किन्तु जिन देशों के बीच प्रत्येक बात में अन्तर एवं विरोध हो वहाँ समझौता सम्भव नहीं हो सकता। पत्रिकार के मतानुसार "विश्व के दो प्रधान गुटों के बीच इतनी गहरी खाई है कि उनके बीच कूटनीतिक सम्बन्ध रह ही नहीं सकते।"

एक ओर तो विभिन्न कारणों के फलस्वरूप कूटनीति का व्यवहार आज के युग में दुरुह बन गया है और दूसरी ओर उसकी आवश्यकता जितनी आज के अणुयुग में है उतनी शायद ही किसी युग में रही होगी। विश्व में शक्ति के लिए सदैव संघर्ष होता रहता है, इस संघर्ष को सीमित एवं सन्तुलित बना कर कूटनीति विश्व में शान्ति स्थापना का एक प्रमुख साधन बनती है। कूटनीति के अभाव का अर्थ होगा 'युद्ध' और युद्ध का अर्थ होगा प्रलय तथा मानव-सम्पत्ति और संस्कृति का विनाश। इस खतरे को टालने के लिए उन तत्त्वों की खोज करना आवश्यक है जो वर्तमान विश्व को परिस्थितियों में भी कूटनीति को सम्भव बना सकें। कूटनीति को पुनः स्थापित करने के लिए पहले तो उन सभी तत्त्वों का मिटाना होगा या कम करना होगा जो कि पुरानी कूटनीति के ह्रास का कारण माने जाते हैं। हेराल्ड निकोलसन (Harold Nicolson) के मतानुसार तीन ऐसे विकास हैं जिन्होंने कूटनीति के सिद्धान्त एवं व्यवहार को प्रभावित किया है—

- (1) राष्ट्रीय समुदाय के प्रति बढ़ती हुई चेतना (Growing Sense of the Community of Nations)
- (2) लोकमत का बढ़ता हुआ महत्त्व (Increasing Appreciation of the Importance of Public Opinion)
- (3) संचार-साधनों का द्रुत विकास (Rapid Increase in Communications)

मॉर्गेंथौ के मतानुसार आज की परिस्थितियों में एक देश की कूटनीति की सफल रूप से कार्य करने के लिए नौ नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें चार मौलिक नियम निम्न प्रकार हैं—

- (1) कूटनीति को आन्दोलनकारी विचारधारा से शृङ्खलित न किया जाए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर युद्ध का खतरा बढ़ जाता है।
- (2) विदेश-नीति को राष्ट्रीय हित के शब्दों में परिभाषित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय शक्ति द्वारा उसे समर्थित किया जाना चाहिए।
- (3) कूटनीति के लिए आवश्यक है कि वह राजनीतिक घटना-चक्र की दूसरी देशों के दृष्टिकोण से देखा जाए।
- (4) एक राष्ट्र को उन सभी विषयों पर समझौता करने की तैयारी रहना चाहिए जो उसके लिए अधिक महत्त्व के नहीं हैं।

समझौतों के सफल होने के लिए पाँच अन्य निगमों का पालन करना चाहिए जो इस प्रकार हैं—

- (1) समझौता करते समय कानून की तरफ ध्यान न देकर ज़रूतों के हित का ही ध्यान रखना चाहिए।
- (2) ऐसी स्थिति में कभी मत रद्द न हो जहाँ से पीछे हटने के लिए तुम्हें अपमानित होगा पड़े तथा आगे बढ़ने के लिए गम्भीर सबट का सामना करना पड़े।
- (3) कमजोर मित्रराष्ट्र को अपने लिए निर्णय बनाने का अवसर न दो।
- (4) सशस्त्र सेना विदेश-नीति का साधन होनी है, उसकी स्वायत्ति नहीं। एक विदेश-नीति, जो सैनिकों द्वारा सैनिक कला के नियमों के अनुसार संचालित होनी है, हमेशा युद्ध का ही कारण बनती है; क्योंकि जैसा बीज बोया जाता है वैसे ही फल भी चखने को मिलते हैं।
- (5) सरकार जनमत का नेतृत्व करती है न कि गुलामी का। लोकमत के पीछे भागने वाली कूटनीति सफल नहीं हो पाती क्योंकि लोकमत विवेकपूर्ण की अपेक्षा भावात्मक अधिक होता है।

कूटनीति के विषय पर अपना निष्कर्ष देते हुए माँगेंबो ने बताया है कि अब तक के इतिहास में कूटनीति सफल ही रही है। प्राचीन समय के राजाओं द्वारा युद्ध रोकने में नहीं बल्कि युद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, अतः वह अपने लक्ष्य में सफल रही यद्यपि शान्ति की दृष्टि में वह असफल थी। किन्तु कूटनीति तो एक साधन मात्र है जिसे एक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा व अभिवृद्धि के लिए अपनाता है। कूटनीति का स्वरूप एवं परिणाम प्रयोगकर्ताओं की योग्यता एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है।

संसदीय कूटनीति (Parliamentary Diplomacy)

संसदीय कूटनीति शब्द के प्रचलन का श्रेय डीन रस्क को दिया जाता है। इसके मतानुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ की बैठकें राष्ट्रीय संसद् से मिलती-जुलती हैं क्योंकि उनमें भी प्रक्रिया के नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है। प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ में जो वाद-विवाद एवं कार्य होता है, अधिकारियों के चुनाव होते हैं, वजेट का निर्धारण होता है और महासचिव का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है वे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका की प्रक्रियाओं के अनुरूप होते हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया के परिणामों को प्रभावित करने के लिए क्षेत्रीय तथा राजनीतिक गुट ऐसे ही प्रयास करते हैं जैसे कि संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय गुटों एवं विशेष हित-समूहों द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाहरी वक्ताओं में प्रतिनिधि मंत्रों का ऐशदान-प्रदान करते हैं, अपनी स्थिति के सम्बन्ध में तर्क देते हैं और अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संयुक्त-राष्ट्रसंघ के अधिवेशन काल भी भोजन-कक्षों में तथा प्रतिनिधियों के विश्राम-स्थलों में विचार-विमर्श होते हैं। महासभा के सत्र के दौरान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संकट

के समय न्यूयॉर्क नगर में विश्व की किसी राजधानी की अपेक्षा अधिक कूटनीतिक क्रियाएँ होती हैं।

समदीय कूटनीति की अपनी कुछ भीमाएँ हैं। यह इस बात पर जोर देती है कि एक मामले को सबके सामने लाने से तथा उस पर वाद-विवाद करने एवं प्रस्ताव पास करने मात्र से सुलझाया जा सकेगा किन्तु यह बात काफी भ्रामक है। व्यावहारिक रूप में इस प्रकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप मनमुटाव और राष्ट्रीय भावनाएँ उभरती हैं। यह भी सम्भव है कि एक राज्य बिना प्रश्न को समझे हुए तथा उसके परिणामों पर विचार किए गए ही प्रस्तावित प्रारूप पर मत प्रदान कर दे। जब पूर्ण मतदान होता है तो उसमें अनुपस्थित रहने वालों की सख्या का महत्व भी हो जाता है। संयुक्त-राष्ट्रसंघ में गुट-राजनीति शक्ति-राजनीति का रूप धारण कर सकती है।

समदीय कूटनीति उपयोगी भी है क्योंकि यह विश्व-जनमत को रोक देने में पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह अनेक देशों के सहयोग को सुविधाजनक बनाती है तथा सामूहिक कार्य के लिए नींव तैयार करती है। इस प्रकार की कूटनीति को अन्य प्रकार की कूटनीति का विकल्प नहीं माना जा सकता।

प्रचार (Propaganda)

राष्ट्रीय हित के साधन के रूप में प्रचार एक बहुत ही प्रभावशाली शस्त्र है। इसका दो रूपों में महत्त्व है। प्रथम तो यह प्रचार द्वारा राष्ट्रीय हित के अन्य साधन जैसे कूटनीति, आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद, युद्ध को अधिक सफलतापूर्वक तथा अधिक प्रभावपूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे, प्रचार स्वयं में भी इतना सश्रिय तथा मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला होता है कि बिना इसके शक्ति-शाली स्वरूप के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, और न वह विश्व-समाज में उच्च स्तर ही प्राप्त कर सकती। आज के प्रजातन्त्र के युग में भी प्रचार के महत्त्व को कई गुना कर दिया है क्योंकि वर्तमान युग में अपनी नीतियों के प्रति दूसरे देशों की सश्रिय सद्भावना प्राप्त करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि आप उस देश के कुछ व्यक्तियों को प्रसन्न करके अपने पक्ष में कर लें वरन् प्रचार के समस्त साधनों द्वारा उस देश की जनता को प्रभावित किया जाता है। अपने देश की नीतियों के पक्ष में जनमत तैयार करके ही उस देश की सरकार को अपने पक्ष में लिया जा सकता है। साम्यवादी देशों द्वारा प्रचार के साधन का उपयोग पूर्ण शक्ति द्वारा किया जाता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करके एवं नई व्यवस्था कायम करने वाले देशों को प्रचार के हथियार की अधिक आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि उनका कार्य वस्तुस्थिति को कायम रखने वालों की अपेक्षा दुगुना है। एक ओर तो उन्हें यह सिद्ध करना पड़ता है कि वर्तमान स्थिति की क्या बुराइयाँ हैं तथा इसे किस प्रकार बदला जा सकता है और दूसरी ओर उन्हें अपनी आदर्श

योजना का चित्र भी खींचना होता है। इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साम्यवादी देश प्रचार के प्रभावशाली यन्त्रों का प्रयोग करते हैं।

प्रचार के प्रभावशाली यन्त्र कोई सुनिश्चित नहीं होते वरन् समय की आवश्यकता एवं नवीन आविष्कारों के प्रवाह में उनका प्रभाव एवं महत्त्व घटता-बढ़ता रहता है। आज के युग में छापाखाना, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, सस्ती पत्रिकाएँ, अखबार, चलचित्र आदि साधनों को प्रचार कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। साम्यवादी देशों को अपने प्रचार में वही सुविधा रहती है जो एक आक्रमणकारी को रहती है। वे प्रचार द्वारा स्थित व्यवस्था की कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रचार का प्रभाव विश्व के छोटे देशों पर अधिक होता है जो शक्तिहीन तथा कमजोर हैं तथा जिनका साम्यवाद का ताकतवर टॉनिक बड़ा खुभावना प्रतीत होता है। दूसरी ओर पश्चिमी प्रजातन्त्रों के पास ऐसा कोई प्रभावोत्पादक टॉनिक नहीं है और उनका साम्राज्यवादी इतिहास भी विश्व के देशों से छिपा नहीं है। इस प्रकार पश्चिमी प्रजातन्त्रों के प्रचार का प्रभाव इतना अधिक नहीं होता। दूसरी ओर साम्यवादी देशों की अपेक्षा इन देशों को प्रचार की इतनी आवश्यकता भी नहीं रहती। इनके प्रचार का मूल लक्ष्य होता है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। अपने प्रचार-यन्त्रों का प्रयोग वे केवल असाम्यवादी देशों में ही कर सकते हैं क्योंकि साम्यवादी देश में साम्यवाद विरोधी विचार एवं प्रक्रिया का प्रवेश असम्भव-सा है। ऐसी समस्या साम्यवादी देशों के प्रचार के मार्ग में नहीं आती।

वर्तमान परिस्थितियों में विश्व का कोई भी देश प्रचार की अवहेलना नहीं कर सकता अन्यथा वह शक्ति-संघर्ष की दौड़ में पिछड़ जाएगा।

प्रचार का अर्थ एवं परिभाषा

(The Meaning and Definition of Propaganda)

प्रचार की आवश्यकता देश में राष्ट्रीय एकता की स्थापना तथा विदेशों में अपनी नीतियों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए इतनी बढ चुकी है तथा व्यक्तिगत, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में प्रचार इतना लोकप्रिय बन चुका है कि इसका अर्थ एवं परिभाषा देने का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय नीतियों का यह प्रमुख अस्त्र बन गया है।

प्रचार का अर्थ सामान्यतः उन कार्यों से लिया जाता है जो दूसरे व्यक्ति को अवसर वक्ष समझाने तथा तदनुकूल आचरण कराने के लिए किए जाते हैं। जोसेफ फॉकेल के शब्दों में, “प्रचार से हमारा अर्थ सामान्यतः किसी भी ऐसे व्यवस्थित प्रयास से होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक प्रदत्त समूह के मस्तिष्कों को, भावनाओं को तथा क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।” प्रोफेसर पॉल एस. लाइम्बर्गर ने भी प्रचार का अर्थ इन्हीं शब्दों में वर्णित किया है। पामर तथा पकिंस के मतानुसार “प्रचार नैतिक रूप में निष्पक्ष होता है; वह जिस तरह अछि उद्देश्य के लिए लोगों को फुसला सकता है उसी तरह बुरे उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है। इसलिए नैतिक निर्णय ‘प्रचार’ पर न दिया जाकर फुसलाने वाले के

उद्देश्यों पर दिया जाना चाहिए।" चार्ल्स बर्ड (Charles Bird) के विचार में, "प्रचार का अर्थ है एक बड़े जन-समूह पर सुनिश्चित एवं व्यवस्थित रूप में मुभावों का प्रयोग करना। यह इसलिए किया जाता है ताकि उन लोगों के दृष्टिकोणों पर नियन्त्रण किया जा सके और उनमें मनमाना आचरण कराया जा सके।" अर्कोत्कर प्रचार को व्यक्ति अथवा एक समूह का संगठित एवं व्यवस्थित प्रयास मानते हैं जो किसी भी क्षेत्र में लोकमन एवं दृष्टिकोणों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार प्रायः सभी विद्वान् प्रचार को परिभाषित करते समय उसे तीन भागों में विभाजित करते हैं अर्थात् यह किनके द्वारा किया जा रहा है (व्यक्ति या समूह)? किस रूप में किया जा रहा है (संगठित एवं व्यवस्थित मुभाव)? क्यों किया जा रहा है (लोकमन के दृष्टिकोणों को या उनके कार्यों को नियन्त्रित करने के लिए)? प्रचार एवं कूटनीति (*Propaganda and Diplomacy*)

कूटनीति अथवा राजनय के माधनों में प्रचार एक महत्वपूर्ण माधन है। राष्ट्रीय हित के अनुसार एवं देश का कूटनीतिज्ञ जब अपने मित्रों और शत्रुओं का चरन करना है तो प्रचार-यन्त्र उसका मुख्य सहायक बनता है। प्रचार के माध्यम से मित्रराष्ट्रों के प्रति नदभावनाएँ व्यक्त करने और उनमें वृद्धि करने तथा शत्रु राज्यों के प्रति विष उगाने में सुविधा रहती है। प्रचार द्वारा विरोधी पक्ष को अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बदनाम किया जाता है, उसके रूप को कलंकित किया जाता है तथा उसके हितों को आघात पहुँचाने के हर अवसर का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर अपने अनुकूल राज्यों में सैद्धीपूर्ण सम्बन्धों का विस्तार करने में प्रचार यन्त्र कदम-कदम पर राजनयज्ञ की सहायता करता है। प्रचार की सहायता से एक राजनेता किसी राज्य में सन्धि के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है तथा सन्धि की प्रभावी बनाने के लिए स्वदेश और विदेश में जनमत तैयार करता है। नाज़ियों के प्रचार-यन्त्र ने तो इतिहास में अपना सौर्जितमान स्थापित कर दिया था। द्वितीय महायुद्ध के समय नाज़ी जर्मनों ने शत्रु-राज्य की जनता को प्रभावित करने के लिए अभिनय तरीकों का अविष्कार किया। कहा जाता है कि उस समय नाज़ी समर्थन में बोलने वाले इनके रेडियो स्टेशन पैदा हो गए थे कि उसके प्रसारण केन्द्र का पता लगाना भी दुष्कर था। गोएबन्स नाज़ी प्रचार यन्त्र का मुख्य मंचालक था जिसने भूट को मच और मच को भूट मिट्ट कर देने में अपने घटमूढ़ कौशल का परिचय दिया। प्रचार द्वारा एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दुनिया को किस तरह मुभावों में डारने की कोशिश कर सकता है, इसका उदाहरण पारितोषान के श्री मुट्टो के इन शब्दों में दूँटना कठिन नहीं है जो उन्होंने घगम्न, 1974 के अपने एक भाषण में बंगलादेश की यात्रा के मन्दर्म में बड़े—

"बंगलादेश की अपनी हाल ही की यात्रा में मैं एक तरह से नज़रबन्द-मा था। मैंने बंगलादेश के लोगों ने मुलाक़ात करनी चाही लेकिन मुज़ीब सरकार ने मुझे मुलाक़ात नहीं करने दी और कहा कि लोगों के बीच जाना आपने लिए ख़तरे में माली नहीं है। मैंने मुज़ीब साहब से कहा कि नहीं ऐसा कोई ख़तरा

नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और बंगलादेश के लोगों से मिलने की मेरी स्वादिष्ट पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान के लिए बंगलादेश के लोगों की मुद्दयन के जजबान इसी बात से जाहिर है कि लोग वहाँ 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगा रहे थे। मुजीब साहब शायद दुनिया को यह जानने देना नहीं चाहते कि बंगालियों में पाकिस्तान के लिए कितना प्रेम है और वे पाकिस्तानियों को आज भी अपना भाई समझते हैं। डार्ड साल की जुदाई के बाद भी मैंने यह देखा कि बंगलादेश में पाकिस्तानियों के लिए जबरबस्त सद्भाव है।¹

दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने बंगलादेश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) की जनता के साथ कंसा 'भाईचारा' निभाया था। पुनश्च, दुनिया जानती है कि हर बार पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोपा, लेकिन पाक-नेतृत्व की प्रचार-कला का नमूना देखिए कि उसने भारत और अफगानिस्तान को चेतावनी दी कि "यदि पाकिस्तान पर युद्ध थोपा गया तो समूचे उपमहाद्वीप और अफगानिस्तान को उसका अजाम मुगलता होगा।"² दरअसल प्रचार रूपी यन्त्र के सहारे कूटनीति कई बातें व्यक्त करती है जिनमें कुछ का उद्देश्य अपने देश और अपने मित्रराज्यों की जनता के मनोबल को ऊँचा उठाना होता है, कुछ का उद्देश्य शत्रुराज्य की जनता के मनोबल को गिराना होता है, कुछ का उद्देश्य विश्व के दूसरे देशों को मुलावे में डालकर उनकी सहानुभूति अर्जित करना होता है तथा कुछ का उद्देश्य सत्य बात को सामने रखकर अपना पक्ष मजबूत बनाना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रायः सभी विचारक कूटनीति में प्रचार के महत्त्व के सम्बन्ध में एकमत हैं। मॉर्गेंथो ने प्रचार की मनोवैज्ञानिक युद्ध (Psychological War) की स्थिति माना है। उन्हीं के शब्दों में, "मनोवैज्ञानिक युद्ध अथवा प्रचार कूटनीति तथा संयुक्त बल के साथ तृतीय शक्ति (Third Force) के रूप में संयुक्त होता है जिसके द्वारा विदेश-नीति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करती है।"³ प्राधुनिक युग में प्रचार का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि कूटनीति और युद्ध के बाद इसे ही राष्ट्रीय नीति की 'तृतीय शक्ति' (Third Force) माना जाता है। प्रचार कभी-कभी वह स्थिति पैदा कर देता है कि बरबस हमें यह शेर याद आ जाता है—

"दहशत में हर नकशा उल्टा नजर आता है,

मजबू नजर आती है, लंला नजर आता है।"

जय सन् 1971 में रेडियो पाकिस्तान से प्रचार के इन गोलों की बार-बार वर्षा हुई, चुनाव के दिनों में भारतीय सेना के दो लाख जवान पश्चिम बंगाल में गोतियाँ चलाते रहे जिससे कई बड़े-बड़े नेता मारे गए या जब इसी प्रकार की अनर्गल बातें सुनने को मिलीं तो राह-चलतों को ऊपर लिखा शेर जरूर याद आया

1 विमल, दिनांक 25 अगस्त 1974, पृष्ठ 5.

2 हिन्दुस्तान, दिनांक 23-3-75.

3 Morgenthau : op. cit., p. 339.

4 विमल, दिनांक 25-4-71, पृष्ठ 7.

होगा। प्रचार का लक्ष्य ही अपने पक्ष को दृढ़ता प्रदान करना होता है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का यह मुख्य लक्ष्य रहता है कि विरोधी के विचारों को परिवर्तित कर अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जाय। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बूटनीति का उपयोग करते हुए कभी तो एक राज्य दूसरे राज्य को आश्वासन देता है और कभी उसे चुनौतियाँ देता है। प्रचार के माध्यम से एक राज्य अपने राष्ट्रीय हित के अनुकूल विश्वास पैदा करने, नैतिक मूल्यों का विकास करने, भावनात्मक प्राथमिकताओं को उभारने तथा लोगों के मस्तिष्कों को बदलते वा प्रयास करता है।

प्रचार विदेश-नीति के एक साधन के रूप में

(Propaganda as an Instrument of Foreign Policy)

स्पष्ट है कि प्रचार-यन्त्र को राज्य विदेश-नीति के साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आज की विश्व-राजनीति में गुटबन्धियों का जाल बिछा हुआ है और प्रत्येक गुट अपने हितों की प्राप्ति के लिए प्रचार-साधनों का प्रयोग करता है। सधेप में, दूसरे गुट को कमजोर बनाने के लिए, उसके सहयोगियों को तोड़ने के लिए, अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए, अधिकाधिक देशों को अपने पक्ष की ओर खींचने के लिए, अपनी विदेश-नीति के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, अपनी शान्ति-प्रियता वा सिक्का बँटाने आदि के लिए प्रचार तकनीकों को विभिन्न रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। प्रचार के माध्यम से विदेश-नीति के लक्ष्यों को परिभाषित किया जाता है। आज सभी देश प्रचार-साधनों का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। सभी प्रचार असत्य हो, यह आवश्यक नहीं है। प्रचार का उद्देश्य किसी राज्य की सरकार को गिराना या दबाना भी हो सकता है और नहीं भी, सत्य बात को सामने रखना भी हो सकता है और गलत बातों को सही रूप में पेश करना भी। यह अपनी-अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर है कि कुछ राज्य प्रचार में नैतिक बल का प्रश अधिक रखते हैं और कुछ नैतिकता-अनैतिकता जैसी बातों की कोई परवाह नहीं करते। अपनी बात से भुकर जाने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता।

प्रचार के उद्देश्य : राष्ट्रीय हित में वृद्धि

(The Objects of Propaganda :

Promotion of National Interest)

प्रचार एक ऐसा साधन है जिसके उद्देश्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ज्ञान के क्षेत्र में इसकी पहुँच है। यहाँ हमारा सम्बन्ध प्रचार के केवल उसी रूप से है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने में समर्थ होता है। पेंडलफोर्ड तथा लिंकन का कथन है कि "प्रचार वा रूप चाहे कुछ भी हो अथवा इसमें किसी भी तकनीक को अपनाया गया हो, इसका मुख्य उद्देश्य नीति एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।"

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला प्रचार केवल एक देश की सरकार द्वारा ही किया जाता हो ऐसी बात नहीं है। गैर-सरकारी व्यक्तियों से भी प्रचार

के इस रूप का प्रयोग हो सकता है। अनेक व्यक्ति, व्यापारिक हित, प्रसारण संस्थान इस प्रकार के कार्य में सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल दूसरे देशों में प्रचार द्वारा अपने राष्ट्र हित के लिए समर्थन प्राप्त करते हैं। समय के अनुसार प्रचार के अभिनव साधनों का विकास होता रहता है।

प्रचार के उद्देश्यों पर यदि हम विचार करें तो ज्ञात होगा कि मूल रूप में सभी प्रचार सम्बन्धी कार्य राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर ही क्रियान्वित किए जाते हैं। ऐसा अनेक रूपों में हो सकता है। उदाहरण के लिए—

प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते जिस समय होते हैं उनको अपने हित में मोड़ने के लिए एक देश प्रचार का सहारा ले सकता है।

दूसरे, किसी समस्या या विशेष प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई सम्मेलन बुलाने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए भी प्रचार का सहारा ले सकता है।

तीसरे, प्रचार द्वारा विचारधारा का प्रचार भी किया जाता है। एक देश के राजनीतिक सदैव दस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि जिस विचारधारा पर उनका देश आरुढ़ है उसी को दूसरे देश भी माने क्योंकि मंत्री एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्धों का दृढ़ आधार विचारों की एकता होती है।

चौथे, प्रचार का सहारा अपनी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।

प्रचार का महत्व युद्ध से पूर्व एवं युद्ध के दौरान बहुत बढ़ जाता है। शान्तिकाल की भाँति सकटकाल एवं युद्धकाल में भी प्रचार द्वारा विभिन्न तरीके अपनाकर राष्ट्रीय हित की साधना की जाती है। कूटनीति और युद्ध के बीच जो संबंधपूर्ण स्थिति रहती है उसमें दो देशों के बीच बड़े कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहते हैं। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर विष वमन किया जाता है तथा दूसरे को गलत ठहरा कर अपनी नीति का औचित्य प्रस्तुत किया जाता है। इस स्थिति को राजनीतिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक राज्य के सामने ऐसे अवसर आते हैं जबकि वह दूसरे राज्यों पर प्रभाव डाल सके। यह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इन अवसरों पर प्रचार का सहारा लिया जाता है। प्रचार द्वारा कभी-कभी राजनीतिक युद्ध (Political Warfare) की सी स्थिति पैदा कर दी जाती है किन्तु ऐसा कि पामर तथा पकिस का कहना है, इन दोनों के बीच अभिसत्ता का सम्बन्ध नहीं है। प्रचार का प्रयोग करने पर आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक युद्ध (Political Warfare) की सी स्थिति पैदा हो जाए, राजनीतिक युद्ध प्रचार का रूप ले भी सकता और नहीं भी ले सकता है, दोनों ही बातें सम्भव हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का इतिहास बतलाता है कि प्रचार के माध्यम से युद्ध के परिणामों को भी बदला जा सकता है।

राज्य की उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए प्रचार वस्तुतः बहुत ही प्रभावशाली साधन है। नाजी जर्मनी की राजनीति पूरी तरह प्रचार पर आधारित थी। प्रचार

को साधन के रूप में प्रमुखता देते हुए हिटलर ने लिखा था, “प्रचार एक साधन है और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है उसी सन्दर्भ में प्रचार को आँकना है। इसे इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए ताकि यह उद्देश्यों की प्राप्ति के योग्य बन सके, और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सामान्य उद्देश्यों का महत्व आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए प्रचार का आन्तरिक रूप भी तदनुसार बदलता रहना चाहिए।”

प्रचार के महत्व को स्वीकार करते हुए अनेक राजनीतिज्ञों और विचारकों ने इसे न केवल राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का भी एक तत्त्व माना है। पामर एव पकिंस ने लिखा है, “प्रचार राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ में अधिकाधिक आवश्यक होता जा रहा है क्योंकि इससे राज्य में संगठित जनमत निर्माण और विदेश में अपने हितों में वृद्धि होती है।” वीसवीं शताब्दी में प्रचार राष्ट्रीय नीति का एक परिपक्व साधन बन गया है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर यदि राज्य प्रचार-यन्त्र का सहारा न ले और प्रभावशाली रूप में प्रचार-नीति का अनुशीलन न करे तो वह निःसंदेह भारी कठिनाई में पँस सकता है। श्रीमती गांधी के हाल ही के नेतृत्व से पूर्व भारत की कूटनीति का प्रचार-पक्ष हमेशा दुर्बल रहा क्योंकि हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक कम और आदर्शवादी अधिक था। लेकिन सन् 1970 से देश ने राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के रूप में प्रचार-साधन पर अधिक बल दिया है और हमारी वर्तमान विदेश-नीति अपने मौलिक सिद्धान्तों का परित्याग न करते हुए अधिक व्यवहारवादी रूप धारण किए हुए हैं।

प्रचार के तरीके (Techniques of Propaganda)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रचार के वे ही तरीके प्रचलित हैं जो व्यापार में विज्ञापन के लिए अपनाए जाते हैं। प्रायः मस्तिष्क में सदैव यह बात रहती है कि लोगों की इच्छाएँ, भय तथा कमजोरियाँ क्या हैं। इन सब के अनुकूल ही नीति तैयार की जाती है। प्रचार करने की विधियाँ अनेक हैं। हार्टर तथा सूलीवान (Harter and Sullivan) ने प्रचार की 12 विधियों का उल्लेख किया है। इनको पामर तथा पकिंस ने चार शीर्षकों में विभाजित किया है¹—

- (क) प्रस्तुत करने की विधि (Method of Presentation)
- (ख) ध्यान-आकर्षण विधि (Techniques for gaining Attention)
- (ग) अनुक्रिया प्राप्त करने की युक्ति (Devices for gaining Response)
- (घ) स्वीकृति पाने के साधन (Methods of gaining Acceptance)

उक्त चारों विधियों को अपनाकर एक देश द्वारा प्रचार-यन्त्र का उपयोग किया जाता है।

(क) प्रस्तुत करने की विधि (Method of Presentation)

इस पहली विधि के अनुसार प्रचारकर्त्ता देश किसी समस्या को प्रस्तुत करते

समय उसका पूरा विवरण नहीं देता, वह केवल उसके उसी पक्ष को प्रकट करता है जो उसके हित में होता है। उदाहरण के लिए भारत-पाक संघर्ष के समय काश्मीर समस्या के बारे में पाकिस्तानी अखबार तथा अन्य स्रोतों से बराबर यही प्रचार किया जाता रहा कि काश्मीर पाकिस्तान का अंग है क्योंकि वहाँ की जनता मुसलमान है और वहाँ के जनमत की माँग है कि काश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, काश्मीर समस्या पर युद्ध छेड़ने का उत्तरदायित्व भारत का है न कि पाकिस्तान का, आदि। इन कथनों के प्रमाणस्वरूप बहुत-सी घटनाओं एवं निर्णयों का हवाला दिया जाता है जो यदि सही रूप में रखी जाएँ तो पाकिस्तान के दावे के विपरीत जाएँ, किन्तु उनको तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है—ठीक उस वकील की तरह जो अपने पक्ष के समर्थन के लिए किसी तथ्य के पूर्ण रूप को देखने की अपेक्षा उसके अजमात्र को ही देखता है। कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन जिन विनो वकालत करते थे एक न्यायाधीश ने उनके तर्कों पर आपत्ति की और कहा, “मि. लिंकन, इस समय आप जो तर्क दे रहे हैं, वे आपके द्वारा ही एक दूसरे के मध्य में कल दिए गए तर्कों के विपरीत हैं।” इस पर लिंकन का उत्तर था, “माई लॉर्ड, हो सकता है कि मैंने कल जो तर्क दिए थे वे गलत हो किन्तु मेरे ये तर्क पूर्णतः सत्य हैं।” प्रत्येक प्रचारक अब्राहम लिंकन के इस उत्तर को ध्यान में रख कर ही अपना कार्य करता है। वह उन सभी तथ्यों को छिपा लेता है जो उसके मामले के विपरीत जाते हों। प्रचार-यन्त्र के कुशल उपयोग से विस्मार्क तथा हिटलर ने कई बार अपने उद्देश्यों को बड़ी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार के प्रचार के कई रूप हो सकते हैं, उदाहरण के लिए—

1. भूतकाल के किसी तथ्य को, जो अन्य किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, आप इस तरह से तोड़-मरोड़ सकते हैं कि वर्तमान में उससे आपके हितों के अनुकूल परिणाम प्राप्त किया जा सके।

2. प्रचार में ऐसी घटनाओं एवं प्रमाणों का अपने पक्ष के समर्थन में उपयोग किया जा सकता है जिनका उद्देश्य कुछ और ही होता है, किन्तु आप उनसे अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। हिटलर यहूदियों के विरुद्ध जर्मनों में रोष भड़काना चाहता था। उसने अनेकों कहानियाँ तथा पुस्तकें पस्तुन की और उनके आधार पर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि यहूदी लोग पूरे विश्व पर राज्य करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रचार का तत्काल परिणाम हुआ और यहूदियों के प्रति जर्मनों में क्रोधान्ति भड़क उठी।

3. प्रचार करते समय झूठ और धोखे का मार्ग सर्वाधिकारवादी और लोकतान्त्रिक दोनों ही राज्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किन्तु दोनों व्यवस्थाओं द्वारा किया जाने वाला ऐसा प्रचार एक ही कोटि में नहीं रखा जा सकता। दोनों के बीच उद्देश्य का अन्तर रहता है। प्रजातान्त्रिक देशों का ऐसा प्रचार तानाशाही देशों की तुलना में प्रायः अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वैसे अपवाद तो प्रत्येक आशा के मिल ही जाते हैं।

4. घटनाओं के सत्य रूप को भी प्रचार का विषय बनाया जा सकता है और यह भी सम्भव है कि ऐसा प्रचार काफी प्रभावकारी सिद्ध हो। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं अन्य नेताओं द्वारा भारतीयों को चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है तो प्रचार सत्य होता है और भारतीयों को जागरूक रखता है। चीन और पाकिस्तान के पिछले आक्रमण और उनका अनुतापूर्ण रवैया इस प्रचार को सम्बल प्रदान करते हैं।

5. प्रायः झूठी और महत्त्वहीन घटनाओं को युद्ध का कारण बना लिया जाता है। भारत-पाक युद्ध-काल में साम्यवादी चीन ने भारत पर भेड़ें चुराने जैसे महत्त्वहीन और भेदे आरोप लगाए और ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न किया कि वह जब चाहे तब भारत पर हमला कर सके। हमला करने का विचार तो उसने पहले बनाया और बाद में इन अनर्गल घटनाओं के अपने विचार को क्रियान्वित करने के लिए प्रचार का विषय बना लिया।

(ख) ध्यानाकर्षण विधि

(Techniques for gaining Attention)

दूसरी विधि—यह विचार-प्रक्रिया की अगली सीढ़ी है। जब प्रचारक के मस्तिष्क में एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न साधन अपनाना प्रारम्भ करता है ताकि दूसरे देशों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया जा सके। ध्यानाकर्षण विधि के प्रमुख रूप ये हो सकते हैं—

1. सरकारी प्रयत्न (Official Devices)—दूसरे देश की सरकार के लिए समय-समय पर नोट्स (Notes) भेजे जाते हैं, विरोध प्रकट किया जाता है और राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के भाषणों का हवाला दिया जाता है। भारत-चीन संघर्ष एवं भारत-पाक युद्ध के समय विरोध-पत्रों का आदान-प्रदान एक सामान्य बात बन गई थी।

2. शक्ति का प्रदर्शन (Power Demonstration)—अपनी मांगों तथा हितों की ओर दूसरे देशों का ध्यान आकर्षित करने का दूसरा तरीका यह भी है कि एक देश अपनी शक्ति बढ़ा ले तथा उसका प्रदर्शन करता फिरे। जल, धन, सशस्त्र सेना की पूरी तैयारी करने पर उस देश की ओर विश्व सशक्त दृष्टि से देखने लगेगा।

3. सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural Programme)—सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा एक देश की जनता को अपने पक्ष में किया जा सकता है। विभिन्न देशों के दूतावासों द्वारा यह प्रबन्ध किया जाता है कि विभिन्न तरीकों द्वारा उनके देश की संस्कृति, रहन-सहन, साहित्य, परम्पराएँ आदि से विदेशों को परिचित कराया जाए।

4. राजनीतिक दौरे (Political Visits)—विदेशों से मित्रता बढ़ाने का एक सफल साधन, जो अब पर्याप्त लोकप्रिय बनता जा रहा है, सरकार के अध्यक्षों के दौरे हैं। एक देश का नेता जब दूसरे देश में सद्भावना यात्रा के लिए जाता है तो उस देश की जनता और नेता दोनों पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सर्वोच्च स्तर पर व्यक्तिगत वार्ता द्वारा पारस्परिक सन्देश का विराकरण करके अनेक विवादास्पद मुद्दों का हल करना वस्तुतः एक प्रभावशाली उपाय है।

5. रचनात्मक कार्यक्रम (Constructive Programmes)—दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अखबारों, पत्रिकाओं, रेडियो आदि द्वारा प्रचार तब तक प्रभावहीन रहेगा जब तक उसके साथ एक रचनात्मक कार्यक्रम को संलग्न न किया जाए। कार्य प्रमुख है और बातें गौण। फामर तथा पकिस ने भी कहा है, "एक रचनात्मक नीति द्वारा प्रचार का अधिकरण कमजोर होने पर भी दूसरे देशों का ध्यान अपने पक्ष में आकर्षित किया जा सकता है।"

(ग) अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने की युक्ति

(Devices for gaining Response)

प्रचार की तीसरी युक्ति द्वारा देशवासियों की अनुकूल प्रतिक्रिया (Response) करने की चेष्टा की जाती है। प्रचारकर्त्ता द्वारा लोगों की देश-भक्ति, आत्मरक्षा एवं न्यायप्रियता आदि की भावनाओं को प्रभावित करके अपनी इच्छानुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। देशवासियों की भावनाओं को प्रभावित करने के लिए अनेकों तरीके अपनाए जाते हैं।

1. नारों का उपयोग (Slogan Tactics)—जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसके लिए एक दो-चार शब्दों का वाक्य रच दीजिए और उसे प्रचारित कीजिए। वह वाक्य लोगों के दैनिक जीवन में घुल-मिल जाएगा, उनके घरों में बच्चे-बच्चे की जबान पर होगा तब निश्चय ही वह उनके कार्यों को भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। 'स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे ने फ्रांस की क्रांति में तथा 'प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं' (No Taxation Without Representation) के नारे ने इंग्लैंड के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसी प्रकार मार्क्स की उक्ति 'दुनिया के मजदूरों एक हो' (Workers of the World Unite) का प्रभाव सभी देशों के मजदूरों में चेतना जाग्रत करने का प्रमुख साधन बन गया है। 'अफ्रीकी एकता', 'अरब एकता', 'जनतन्त्र खतरे में है', आदि आधुनिक नारे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को काफी प्रभावित किए हुए हैं।

2. प्रतीकों का प्रचलन (Symbolic Devices)—नारों की भाँति प्रतीक भी मनुष्य की भावनाओं को प्रभावित करने में बहुत सफल रहते हैं। देशवासियों में भावनात्मक एकता पैदा करने एवं राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा चित्र, जानवर, संकेत, राष्ट्रीय, झण्डा एवं अनेक प्रकार के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इतिहास में सबसे प्रभावशाली प्रतीक की भूमिका नाजी जर्मनी में 'स्वस्तिक' की थी। राष्ट्रीय नेताओं के रूप में चर्चित, रुजवेल्ट, स्टालिन, नेहरू आदि ने प्रभावशाली प्रतीकों का कार्य किया।

3. विचारों का व्यक्तिकरण (Personification of Ideas)—विचारों के साथ व्यक्ति को एकाकार कर दिया जाता है। एक व्यक्ति जब यह कहता है कि वह महात्मा गाँधी का अनुयायी है तो तुरन्त ही हमारा मस्तिष्क यह स्वीकार कर लेता है कि उस व्यक्ति में शान्ति, अहिंसा और सत्य आदि गुणों के प्रति श्रद्धा है। गुट-निपेक्षता की विदेश नीति (Non-Aligned Foreign Policy) का प्रसंग छिड़ते

ही हमारे मानस-पटल पर स्वर्गीय प. नेहरू का चित्र उभर आता है। व्यक्ति को प्रायः उस देश के साथ एकाकार कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने के पीछे यही भावना है।

4. परिस्थिति और दृष्टिकोणों का उपयोग (Utilization of Situations and Attitudes) — एक सफल प्रचारक वह माना जाएगा जो परिस्थितियों और दृष्टिकोणों का लाभ उठा कर उन्हें अपने हित में मोड़ ले और उनका प्रचार करे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में सुरक्षा और आर्थिक संकट की जो स्थिति पैदा हुई उसके कारण वहाँ के लोग हिटलर की तानाशाही को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। साम्यवादी चीन ने भारत विरोधी प्रचार कर पाकिस्तान की मैत्री प्राप्त कर ली। पामर एवं पॉक्स के मत में “प्रत्येक प्रचारक वर्तमान दृष्टिकोणों से लाभ उठा कर उन्हें ऐसी दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है जिससे उसका हित-साधन हो सके।”

(घ) स्वीकृति प्राप्त करने के साधन

(Methods of gaining Acceptance)

प्रचार-प्रक्रिया की अन्तिम सीढ़ी अपने प्रचारित लक्ष्यों पर स्वीकृति प्राप्त करने की है। प्रचारक द्वारा ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जिनके द्वारा दूसरे देश उसकी नीतियों को स्वीकृति प्रदान करें। अपनी योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रचार के विषय एवं वस्तु के बीच का भेद मिटा दिया जाए। आपका प्रचार तब तक महत्त्वहीन रहेगा जब तक कि उन लोगों के साथ आप एकाकार न हो जाएँ या घनिष्ठ रूप में घुल-मिल न जाएँ जिनमें प्रचार करना चाहते हैं।

प्रचार पर स्वीकृति प्राप्त करने का दूसरा तरीका है धर्म और जाति के नाम पर प्रभावित करना। मनोवैज्ञानिक रूप से यह सच है कि यदि व्यक्ति आप में और अपने आप में समानता देखने लग जाए तो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। यह समानता धर्म और जाति के नाम पर भी स्थापित की जा सकती है। भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर मुस्लिम देशों से सहायता प्राप्त करने की कोशिशें की थीं। टर्की आदि देश उसके प्रचार के प्रभाव में आकर ‘जिहाद’ का समर्थन करने को प्रसन्न हुए थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय आर्य जाति की श्रेष्ठता के नाम पर हिटलर ने जर्मनी को अपने प्रचार से बशीभूत कर लिया था।

प्रचार को प्रभावकारी बनाने के लिए एक तीसरा तरीका अपनाते समय धर्म की दुहाई दी जाती है। ईश्वर के नाम पर आज तक अनेकों युद्ध लड़े गए हैं। भारत पर होने वाले प्राचीन मुस्लिम आक्रमणों के पीछे धर्म-प्रचार की भावना ही थी। धर्म के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया और आज इजरायल धरम संधर्ष विश्व-शान्ति के लिए महान् संघर्ष बना हुआ है।

प्रचार की प्रक्रिया के इन स्तरों के सम्बन्ध में विधावी नटम उठाने से प्रचार को सफल बनाया जा सकता है। किन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक

प्रचार को उसके विरोधी प्रचार का भी सामना करना पड़ता है। विरोधी प्रचार भी एक प्रतिद्वन्द्वी के रूप में दूसरे का ध्यान आकर्षित करने, अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने एवं उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयास करता है। प्रचार पर सरकार का नियन्त्रण रहता है, ऐसा किए बिना कोई भी शासन सफल रूप से कार्य नहीं कर सकता, किन्तु इस नियन्त्रण के रहते हुए भी एक देश की जनता बाकी विश्व के प्रचार के प्रभावों से पूर्णतः अछूती नहीं रह सकती।

प्रचार के क्षेत्र में प्रतिद्वन्द्विता बहुत रहती है, इसलिए प्रचार-क्रिया में एक तत्त्व यह भी जोड़ना पड़ता है कि विरोधी प्रचार का खण्डन किया जाए। विरोधी का खण्डन करते समय उसके विपरीत तरह-तरह के नारों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के रूप में उन सभी शक्तियों को ले सकते हैं जो पश्चिमी प्रजातन्त्र साम्यवादी देशों के लिए तथा साम्यवादी देश पश्चिमी प्रजातन्त्रों के लिए प्रयुक्त करते हैं। पामर तथा पकिंस के शब्दों में, "यह एक प्रमुख तथ्य है कि प्रायः प्रत्येक पक्ष प्रचार की प्रभावशीलता को रोकने के लिए उसका प्रतियोगी रहता है।"

विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ प्रचार के नए-नए साधनों का प्रचलन होता जा रहा है। प्रचार की प्रक्रियाएँ एवं विधियाँ भी समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती हैं।

प्रभावशाली प्रचार की आवश्यकताएँ (The Requisites for Effective Propaganda)

प्रभावशाली प्रचार के लिए कई बातें जरूरी होती हैं जैसे उसकी सरलता, रुचि, उपयुक्तता, आदि। प्रचारक को अपना विशेष उद्देश्य प्रभावी रूप से प्रचारित करने के लिए समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान, सामूहिक विश्लेषण आदि का सहारा लेना होता है। यह प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विभिन्न माध्यमों द्वारा एक बात को कई बार दुहराया जाए ताकि श्रोतागण उसे भली प्रकार सुन सकें। श्रोताओं पर प्रभाव डालने के लिए प्रचारित विषय को देखने, सुनने और पढ़ने योग्य बनाया जाए। ये सब बातें एक प्रचार कार्य की प्रभावशाली बना देती हैं।

प्रचार कार्य की वस्तुनिष्ठता (The Objectivity of Propaganda) —

इसका सरल तरीका यह है कि खबरों तथा सूचनाओं को यथासम्भव वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए और श्रोता अथवा पाठक को स्वयं ही अपने निर्णयों पर पहुँचने के लिए अवसर प्रदान किया जाए। सीधी और बिना मिलावट की सूचना राजनीतिक दृष्टि से प्रभावकारी होती है। इसका प्रभाव उस समय और भी अधिक होता है जबकि यह उन सर्वाधिकारवादी राज्यों पर प्रभाव डालती है जो सूचना की नियन्त्रित रखते हैं। वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यात्मक सूचना का लाभ यह है कि श्रोता उसे यह जानने के लिए सुनना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी खबरें सुनी है उनमें सत्य का कितना अंश है। वैसे पूर्ण सत्यता तो प्रायः प्राप्त नहीं हो पाती।

द्वितीय विश्व युद्ध काल में बी. बी. सी. को वस्तुनिष्ठता के लिए पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हो गई थी।

बड़ा झूठ और उसका दोहराव (Big Lie and its Repetition)—प्रचार-कार्य को प्रभावशाली बनाने की एक तकनीक यह है कि कोई बड़ा झूठ बोला जाए और उस झूठ को बार-बार दोहराया जाए। हिटलर का विश्वास था कि यदि एक बहुत बड़े झूठ को बार-बार दोहराया जाता है तो वह जनता का विश्वास प्राप्त कर लेता है। अधिकांश जनता में यह समझने की कल्पना नहीं होती कि बार-बार दोहराए जाने वाले कथन पूर्णतः सत्य नहीं होते। इस तकनीक को प्रभावकारी बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों पर नियन्त्रण रखना जरूरी है ताकि परस्पर विरोधी बातें सामने न आएँ। छोटे स्तर का झूठ कम लाभदायक होता है और इससे खबर देने वाले की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है।

सरलता (Simplicity)—जनता के मस्तिष्क पर सीधे-सीधे नारों का अधिक प्रभाव होता है। वह विभिन्न राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधाराओं के तुलनात्मक गुणों के सम्बन्ध में तर्क-वितर्क सुनने की अपेक्षा सरल नारे सुनना अधिक पसन्द करती है। जैसे—‘सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण’, ‘बम पर रोक लगाओ’ तथा पूंजीवादी, साम्राज्यवादी आदि। हंगरी के ‘स्वतन्त्रता सेनानियों की प्रशंसा की गई।’ इसी प्रकार आज के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में स्वतन्त्र विश्व (Free World) और शीत-युद्ध (Cold War) पर्याप्त सामान्य शब्द बन गए हैं।

रुचि एवं आकर्षण (Interest and Attraction)—प्रचार उस समय तक प्रभावहीन रहता है जब तक कि वह सुनने वालों को रुचिकर न लगे। एशिया और अफ्रीका के जिन देशों का सम्बन्ध आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय निर्माण से है वहाँ संयुक्तराज्य अमेरिका जब साम्यवाद को रोकने पर जोर देता है तो इन देशों पर इसका प्रभाव नहीं होता। किसी विषय पर लोगों की रुचि उतनी ही कम हो जाती है जितना कि वह उनसे दूर है। दूसरी ओर संयुक्तराज्य अमेरिका के सूचना-अभिकरण के एक प्रकाशन में अफ्रीका से सम्बन्धित लेख छपते हैं और अफ्रीकी पाठकों को यह अनुभूति देते हैं कि अमेरिका उनके मामलों में रुचि लेता है। प्रचार-कार्य को रुचिपूर्ण बनाने के लिए शारीरिक प्रदर्शन एवं दृश्य प्रभाव भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

स्पष्टता एवं प्रामाणिकता (Clarity and Factuality)—यदि प्रचार का विषय बनावटी है या झूठी प्रकृति का है तो उससे प्रायः वाञ्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। प्रचार भी दीर्घकालीन नीति के साथ संयुक्त होना चाहिए। किसी भी प्रचार पर तब विश्वास किया जाता है जब उसके अनुसार कार्य भी किया जाए।

स्थानीय अनुभवों एवं दृष्टिकोण में समरूपता (Identification with Local Experiences and Outlook)—प्रचार-कार्य लोगों का अपनी ओर ध्यान ही आकर्षित नहीं करना चाहता बल्कि उनकी प्रतिक्रिया भी चाहता है। प्रचारक जिनको प्रभावित करना चाहता है उनकी स्थानीय रुचियों, अनुभवों एवं दृष्टिकोणों का ध्यान

रख कर अपने और उनके बीच की दूरी को मिटाता है। एक प्रभावशाली प्रचारक वह है जो सामान्य विशेषताओं और सामान्य रुचियों पर जोर देता है। साम्यवादी रूस द्वारा विकासशील देशों की एकता का नाम लेकर इसी तकनीक को अपनाया जाता है। संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा जो साम्यवाद विरोधी भावनाएँ फैलाई जाती हैं उनका प्रभाव कम होता है क्योंकि दूसरे लोग प्रायः उनमें विश्वास नहीं करते।

स्थिरता (Consistency)—जोसफ फ्रैंकल (Joseph Frankel) का यह कहना उपयुक्त है कि “प्रचार का प्रभाव उसकी निरन्तरता एवं स्थिरता के कारण बहुत बढ जाता है। साथ ही सूचना के प्रतियोगी स्रोतों को समाप्त कर देना भी उपयोगी रहता है।” आर्थर क्रीक (Arthur Krock) का कथन है कि एक प्रजातन्त्रात्मक सरकार को अपना प्रचार प्रभाव बनाने के लिए अपने कथनों की सत्यता वास्तविक कार्यों से सिद्ध करनी चाहिए। प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था अपनी असफलताओं को नहीं छिपा सकती। दूसरी ओर स्वेच्छाचारी सरकार अपनी असफलताओं तथा असमर्थियों को छिपा सकती है और छिपाती है। इस प्रकार की सरकारों का प्रचार उनके कार्यों से मेल नहीं खाता है और रातों-रात उल्टा बन सकता है।

सूचना और प्रचार के रूप

(The Types of Information and Propaganda)

प्रचार-कार्यक्रम के लक्ष्य अथवा उद्देश्य अनेक होते हैं और ये कर्ता के उद्देश्य के आधार पर समय-समय पर बदलते रहते हैं। प्रचार अथवा सूचना के उद्देश्य के आधार पर ही उसका रूप भी निश्चित किया जाता है। प्रचार के विभिन्न रूपों एवं प्रकारों में से कुछ ये हैं—

1. **समाचार एवं सूचना (News and Information)**—इस प्रकार का अधिकांश प्रचार खबर देने के अलावा और कुछ नहीं करता तथा सुनने वाले की स्वयं ही निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए आमन्त्रित करता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक संचार में आंग्ल अमेरिकी प्रयासों की विशेषता है। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में संयुक्तराज्य अमेरिका ने जो प्रचार-नीति अपनाई उसे सत्य की रणनीति (Strategy of Truth) कहा जाता है। आज के संयुक्तराज्य अमेरिका का सूचना-प्रभिकरण दूसरे देशों की जनता को प्रभावित करने के लिए और विदेशों में संयुक्तराज्य का चित्र प्रस्तुत करने के लिए तथ्यों एवं स्पष्टीकरणों का एक प्रमुख साधन के रूप में प्रयोग करता है। इस दृष्टि से हमें तकनीक भी प्रभावशाली बनती जा रही है। सत्य प्रतिबेदन अथवा समाचार के आधार पर एक प्रचार-यन्त्र स्रोतों का विश्वास प्राप्त कर लेता है और यह एक बड़ी उपलब्धि है।

2. **चयन द्वारा तथ्यों को मोड़ना (To Distort the Facts through Election)**—जब एक देश विदेशी जनमत को एक विशेष रूप देना चाहता है तो वह तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उसके सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की संचार-व्यवस्था में ईमानदारी जैसी चीज नहीं रहती और रणनीति की दृष्टि से कभी भी

भूठ को अपनाया जा सकता है। इस प्रकार प्रचार के दो मार्ग दिखाई देते हैं। एक मार्ग यह है कि भूठे तथ्यों को सामने लाया जाए और दूसरा यह है कि भूठे तथ्यों को प्रचारित किया जाए। इन दोनों के बीच का भी एक मार्ग होता है और वह यह कि भूठ तो न बोला जाए लेकिन कुछ तथ्यों को छिपा लिया जाए ताकि लोग सत्य को समझ न सकें। इस मार्ग को अपना कर प्रचारक उन तथ्यों पर अत्यधिक जोर देता है जो सत्य तो हैं किन्तु उसके पक्ष में हैं। दूसरी ओर वह उन तथ्यों की ओर से श्रोताओं का ध्यान हटा देता है जो सत्य होते हुए भी उसके पक्ष में नहीं हैं। इस प्रचार द्वारा भावनात्मक व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रचार में प्रचारक यह सिद्ध करता है कि वह स्वयं निरपराध है और जो भी गलती की गई है वह सब विरोधी द्वारा की गई है। दोनों पक्ष अपने शान्ति-प्रेम की दुहाई देते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि उन्होंने इस प्रेम के निर्वाह में क्या बलिदान किया और दूसरे पक्ष ने उन पर क्या अत्याचार किए। इस प्रकार के प्रचार में तथ्यों की जानकारी का कार्य श्रोता पर छोड़ दिया जाता है। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की तस्वीर खींची गई है। यदि वह उस तस्वीर को मिटा कर दूसरी नहीं बना सकता तो निश्चय ही वह आश्चर्यकारी या साम्राज्यवादी समझा जाएगा। इस प्रकार का प्रचार विदेशों में दृष्टिकोणों को ढालने के लिए तथा दूसरों पर दबाव डालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रचार के इस रूप में तथ्यों को अथवा तथ्यों से मिलती-जुलती चीज को केन्द्र-विन्दु बनाया जाता है और अपने स्वार्थ की दृष्टि से उनकी व्याख्याएँ की जाती हैं।

3. आच्छादित प्रचार (Covert Propaganda)—कभी-कभी प्रचार-कार्य में ऐसे साधन अपनाए जाते हैं जो दृष्टि से ओझल होते हैं। अनेक देश ऐसा करते हैं कि वे अन्य राज्यों के समाचार-पत्रों एवं प्रकाशनों को खरीद लेते हैं तथा उनसे पक्षपातपूर्ण तथा मिथ्या वृत्तान्तियाँ प्रकाशित करवाते हैं जो स्पष्टतया उनके स्वयं के ही हित में होती हैं। जनता की मान्यताओं एवं प्रतिभूतियों को बदलने के लिए दुनिया के विभिन्न भागों में विशेष रूप से तैयार की गई फिल्में वितरित की जाती हैं। इन फिल्मों के मूल निर्माता एवं प्रसारक का नाम प्रकट नहीं किया जाता। जब शुद्ध भूठ का प्रचार किया जाता है तो वह सामान्य जन को स्वीकार्य नहीं होता क्योंकि वह नैतिक दृष्टि से गलत है और प्रचारक की बदनामी होने का डर रहता है। भूठे तथ्यों दीर्घकालीन नीति के रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होते।

किसी तथ्य विशेष की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी सूचना का प्रसार किया जा सकता है और उससे ध्यान हटाने के लिए भी। निम्नी प्रेस-सम्मेलन में किए जाने वाले प्रश्न भी एक विशेष समस्या को अधिक प्रकाश में लाने के लिए किए जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रचार-कार्य के लिए कभी-कभी विशेष संचार-साधनों का प्रयोग किया जाता है। जब इस प्रकार के समाचार सामने आते हैं तो उस देश की सरकार प्रायः उनको छिपाने का प्रयास करती है तथा उनके अस्तित्व को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करती।

4. **प्रादर्शवादिता का प्रचार (Propaganda of Idealism)**—राज्य विचारधारा को आधार बना कर भी दूसरे देशों पर बांछित प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी देश स्वतन्त्रता की आवश्यकता एवं महत्त्व का प्रचार करके अपने विश्वासों एवं मान्यताओं को दूसरे देशों द्वारा स्वीकृत कराने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर साम्यवादी देश अन्य राज्यों में युवकों के आन्दोलनों को प्रोत्साहन देते हैं तथा उन्हें समाजवादी आन्दोलन के पवित्र कार्य में सहयोग करने के लिए प्रभावित करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय युवक समारोह के माध्यम से प्रचार-कार्य के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाना है।

5 **विचार सुधार (Thought Reform)**—कुछ साम्यवादी देश राष्ट्र व्यापी आधार पर विचारों को सुधारने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास किया जाता है कि पश्चिमी देशों के प्रति कटुवाहक पैदा की जाए तथा देश के लोगों के विचारों के तरीकों को निर्देशित किया जाए। साम्यवादी व्यवहार के प्रति तथा साम्यवादी लक्ष्यों के प्रति रुचि पैदा की जाती है। देश, समाज, संस्थाओं एवं मूल्यों के प्रति यहाँ स्वानिर्भरता का उपदेश दिया जाता है। साम्यवादी चीन द्वारा अब ये तकनीकें सोवियत रूस के सशोधन के विरुद्ध भी प्रयुक्त की जा रही हैं।

सोवियत रूस का प्रचार-यन्त्र

(Propaganda Machinery of U.S.S.R.)

द्वितीय महायुद्ध का पूर्वकाल—द्वितीय महायुद्ध से पूर्व सोवियत रूस में प्रचार का तत्त्व एक तो पार्टी और सरकार के तावासाही नियन्त्रण को संगठित बनाया था, दूसरे अपने कार्यक्रम के लिए अनुयायी प्राप्त करना था और तीसरे, लोगों को मातृभूमि के लिए बलिदान करने, कष्ट सहने और मर जाने के लिए तैयार करना था। इस काल में सोवियत प्रचार की मुख्य विशेषताएँ ये थी—

1. उसका प्रचार देश के सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के व्यक्तियों को प्रभावित करना था। दल के कार्यकर्त्ताओं ने स्थानीय सोवियतों, कस्बों, गाँवों और सेना तक अपना सन्देश पहुँचाया तथा समाज के सभी वर्गों, किसानों, मजदूरों सिपाहियों, बुद्धिजीवियों तथा जातीय छल्पसत्यक समुदायों आदि को समझाया कि साम्यवादी समाज वर्गभेद, संघर्ष और पूँजीवाद से मुक्त रहेगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्राप्त होगी।

2. साम्यवादियों ने अपने प्रचार के लिए नवीन शब्दों को चुना। अपने पक्ष-समर्थन एवं विरोधियों के सन्दर्भ के लिए ऐसे शब्दों को चुना जो बहुत प्रभावकारी थे। बाद में ये शब्द साम्यवादी जगत में लोकप्रिय बन गए।

3. साम्यवादीयों द्वारा अनेकों नए नारों का उपयोग किया गया तथा अनेकों प्रतीक जैसे ताल चितारा, हथौड़ा व हसियाँ आदि का प्रयोग किया गया।

4. प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जब रूसी भ्रान्ति सफल हो गई तो प्रचार का एक लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद बन गया। इसके लिए कांमिटर्न (Comintern) आदि संस्थाएँ स्थापित की गईं जो विश्व के दूसरे देशों के साम्यवादी दलों को भी

निर्देशन देती थी तथा दूसरे देशों पर ऐसी विदेश-नीति अपनाने के लिए दबाव डालती थी जो सोवियत रुख के अनुकूल हो। सन् 1935 के बाद यूरोपीय देशों के साम्यवादी दलों ने मास्को के निर्देशन पर ही नाजी जर्मनी के विरुद्ध उदारवादी समुदायों से सहयोग करना चानू किया था।

द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तर काल—द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत रुस के प्रचार की लक्ष्य-प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर आ गया। इसका क्षेत्र केवल राष्ट्रीय न रह कर अन्तर्राष्ट्रीय अधिक बन गया तथा इसका प्रयोग शीतयुद्ध को बनाए रखने के लिए किया गया। पामर तथा पक्सिस के मतानुसार सन् 1945 से 47 तक सोवियत प्रचार के दो लक्ष्य थे—(1) जन प्रजातन्त्र के विकास को प्रोत्साहन, और (2) अमेरिका के प्रभाव को कम करना। महायुद्धोत्तर काल में किए गए सोवियत प्रचार की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं।—

1. साम्यवादी प्रचार का क्षेत्र मुख्य रूप से अर्द्धविकसित या अविकसित देशों को बनाया गया।

2. साम्यवादी जीवन-पद्धति की प्रशंसा की गई और पूँजीवादी राष्ट्रों के अत्याचारों और शोषणों का रक्तरेजित काला चित्र खींचा गया।

3. पूर्व में चीन तथा पश्चिम में यूरोप में साम्यवाद फैलाने के लिए प्रबल व प्रभावकारी प्रचार किया गया।

4. अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों को दी जाने वाली आर्थिक व सैनिक सहायता को उसके साम्राज्यवाद का ही दूसरा रूप माना गया। पत्रों और लेखों द्वारा यह जोरदार प्रचार किया गया कि अमेरिका दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है।

5. सोवियत रुस ने शान्ति अभियान शुरू किया। प्रचार द्वारा सोवियत जनता एवं विश्व के लोगों को यह बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया कि रुस अपनी पूर्ण शक्ति से शान्ति स्थापना के लिए तत्पर है तथा अणु-अस्त्रों को मिटा कर वह निःशस्त्रीकरण करना चाहता है।

6. कोरिया के मामले पर सोवियत प्रचार बहुत प्रभावशाली रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने ही रुस ने यह प्रचार प्रारम्भ कर दिया कि कोरिया की जनता अमेरिकी नीति व व्यवहार के प्रति असन्तुष्ट व क्षुब्ध है और रुस की प्रशंसा करती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की तुलना करके यह प्रचारित किया गया कि अमेरिका कोरिया को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। वियननाम, इजरायल आदि के मन्दर्भ में भी रूसियों द्वारा इसी प्रकार के तर्क दिए जाते रहे हैं।

मयुक्तराज्य अमेरिका का प्रचार-यन्त्र

(Propaganda Machinery of U.S.A.)

सोवियत रुस की तुलना में अमेरिका ने प्रचार के महत्त्व को बाद में समझा। मुनगे सिद्धान्त पर चलाने वाले देश के लिए प्रचार का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई

महत्त्व नहीं था। किन्तु जब रूस में साम्यवाद का उदय हुआ और साम्यवादी प्रचार के तीक्ष्ण वाणियों ने पश्चिमी प्रजातन्त्रों को घायल कर दिया तथा अनेक कारणों से जब अमेरिका को द्वितीय विश्वयुद्ध में सक्रिय भाग लेना पड़ा तो उसे ज्ञान हुआ कि राष्ट्रीय हित के साधन के रूप में प्रचार का कितना महत्त्व होता है।

1. द्वितीय विश्वयुद्ध-कालीन प्रचार—युद्ध काल में विदेशों में मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक युद्ध छेड़ने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई जंगे युद्ध सूचना कार्यालय (OWI) तथा ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित (PWD-SHAEF) आदि। इन संस्थाओं द्वारा राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक युद्ध के संचालन के लिए अनेक तरीके अपनाए गए। जर्मन मनोबल (Morale) को गिराने की चेष्टाएँ की गईं।

युद्धकाल में मित्रराष्ट्रों (अमेरिका, रूस और ब्रिटेन) के रेडियो स्टेशन मिलते-जुलते थे। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के थे। एक सफेद (White) स्टेशन कहलाता था जिसके द्वारा जर्मनी के लिए खबरें तथा परामर्श प्रसारित किए जाते थे। दूसरा काला (Black) स्टेशन था जो था तो मित्र राष्ट्रों का, किन्तु अपने आपको जर्मन कहता था। इसका उद्देश्य था शत्रु को भ्रम में डालना और सच वान की जानकारी के लिए मित्रराष्ट्रों के प्रसारणों को सुनने के लिए सुविधा प्रदान करना। तीसरे प्रकार के स्टेशन भूरे (Grey) थे जो न तो जर्मन होने का दावा करते थे और न मित्रराष्ट्रों के।

युद्ध के अन्तिम दिनों में कुछ सेनापतियों ने लाउडस्पीकरों को अपने अग्रिम दैहो पर लगवा दिया ताकि शत्रु को आत्म-समर्पण करने के लिए प्रोत्सायित जा सके।

इस काल का मित्रराष्ट्रों का प्रचार तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए किए गए उनके प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। उन्होंने जो मार्ग अपनाए, शत्रु उन्हें पहले से ही अपना रहा था। मित्रराष्ट्रों के प्रचार की असफलता के कई कारण थे—

1. प्रारम्भ में मनोवैज्ञानिक युद्ध की जो उच्चस्तरीय योजनाएँ बनाई गईं उनको शत्रु के विरुद्ध नित्याविवृत नहीं किया गया। यदि प्रचार द्वारा जापान के मनोबल (Morale) को गिरा दिया जाता तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध द्वारा उसे कमजोर बना दिया जाता तो वहाँ बम गिराने का व रूस द्वारा उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

2. एक दूसरी बड़ी गलती यह की गई कि मित्रराष्ट्रों ने अपने प्रचार द्वारा जर्मनों के सामान्य नागरिकों और शासन के बीच कोई भेद नहीं किया। उनके प्रचार के फलस्वरूप वहाँ के नागरिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मित्रराष्ट्र न केवल नाजी सरकार के ही नहीं उनके भी दुश्मन अतः उन्होंने नाजी शासन का पूरा-पूरा समर्थन किया। नाजी प्रचार-यन्त्र के संचालक गोएबल्स (Goebbels) ने कहा था कि "अगर मैं शत्रु पक्ष में होता तो नाजीवाद के विरुद्ध लड़ने का नारा लगाता, न कि जर्मन-जवता के विरुद्ध।"¹

2. युद्ध के बाद अमेरिकी प्रचार—शीतयुद्ध के प्रवाह के साथ अमेरिकी जनता और सरकार द्वारा प्रचार के महत्व को समझा जाने लगा। सन् 1948 में स्मिथ मंड एक्ट (Smith Mundt Act) पास किया गया। इसका उद्देश्य था कि अमेरिकी जनता और विश्व की जनता के बीच सद्भावना की स्थापना की जाए। प्रचार से सम्बन्धित नवीन योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई। सन् 1951 में राज्य विभाग (State Department) के अन्तर्गत एक पृथक् अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रशासन (IIA) स्थापित किया गया। 1 अगस्त, 1953 को राष्ट्रपति द्वारा संयुक्तराज्य सूचना अभिकरण (USIA) की एक स्वतन्त्र कार्यालय के रूप में स्थापना की गई। इसको समुद्रपार के सूचना कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

USIA ने विश्व में बड़ी संख्या में सूचना-चौकियाँ स्थापित की हैं। यह असाध्यवादी देशों के हजारों अखबारों के लिए करोड़ों की संख्या में पर्चे, पोस्टर, अखबार एवं पत्रिकाओं के लिए विशेष सामग्री, व्यंगचित्र तथा सूचना सम्बन्धी सामग्री आदि भेजती है। 'वाइस ऑफ अमेरिका' (Voice of America) भी USIA का एक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध भाग है। यह लगभग 38 भाषाओं में प्रतिदिन चौबीस घण्टे प्रसारण करता है। इसके अधिकांश प्रसारणों का निशाना साम्यवादी देश होते हैं।

अमेरिकी प्रचार में से अधिकांश तो प्रचार की प्रतिव्रिया (Counter Propaganda) होता है। इसके अतिरिक्त विदेश-नीति के मुख्य तथ्यों को भी प्रचारित किया जाता है। मार्शल योजना का प्रचार प्रभावकारी रूप में किया गया था।

प्रचार में सरकार के अतिरिक्त निजी संस्थाएँ भी अपना सहयोग प्रदान करती हैं। अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और नुमाइशों में अमेरिका के निजी संगठनों एवं व्यापारिक संस्थाओं ने सक्रिय रूप से उत्साहपूर्वक भाग लिया है।

अमेरिकी प्रचार साम्यवादी देशों की तुलना में कम प्रभावशाली है; पामर तथा पकिस्तान ने इसके दो कारण बताए हैं—

1. सोवियत यूनियन का प्रचार के क्षेत्र में अनुभव अधिक है अर्थात् साम्यवादी प्रान्ति के पूर्व से ही वे इसके अभ्यस्त हैं। इसके बाद अनेकों ऐसे अवसर आए जबकि उनको इसे एक प्रभावकारी अस्त्र के रूप में अपनाना पड़ा था।

2. अमेरिकी प्रचार भाषण की स्वतन्त्रता पर आधारित है, सरकारी नियन्त्रण पर नहीं।

सांस्कृतिक सम्बन्ध और विदेश-नीति

(Cultural Relations and Foreign Policy)

सूचना कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक देश सांस्कृतिक माध्यम से भी अपना प्रचार-कार्य संचालित करते हैं। यह कहा जाता है कि ज्ञान के आदान-प्रदान का सर्वाधिक प्रभावी तरीका यह है कि व्यक्ति को अपने साथ बंध लिया जाए। पश्चिमी

शक्तियों परस्पर शैक्षणिक सम्बन्धों के माध्यम से एक दूसरे के पर्याप्त निकट आ गई हैं। उन देशों के हजारों छात्र एक दूसरे के देश में अध्ययन करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अपने उपनिवेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध थे, इसीलिए वह अधिकांश को शान्तिपूर्वक प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्रदान करके राष्ट्रमण्डल के आधार पर उसने इस सांस्कृतिक सम्बन्ध को कायम रखने की व्यवस्था कर ली। इन देशों के नेताओं को ग्रेट ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, उसके कारण वे यहाँ के मूल्यों तथा मूल राजनीतिक एवं कानूनी संस्थाओं की सराहना करते हैं।

फ्रांस वह पहला बड़ा देश है जिसने सांस्कृतिक सम्बन्धों को सरकारी कर्तव्य बना दिया था। फ्रांस के उदाहरण को देख कर 19वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में इंग्लैंड तथा जर्मनी ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए। ब्रिटेन की दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप तथा अमेरिकी मिशनरियों एवं अमेरिकी सरकार के प्रयास से आज अर्द्धविकसित देशों के लगभग दस मिलियन (एक करोड़) से भी अधिक लोग अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं तथा इनके माध्यम से वे सरकारें इन क्षेत्रों में आसानी से संचार व्यवस्था-संचालित रख सकती हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका का सांस्कृतिक कार्यक्रम—अमेरिका में सन् 1938 में राज्य विभाग के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों का एक सम्भाग जोड़ दिया गया। इसने सबसे पहले लैटिन अमेरिका पर अपना ध्यान आकर्षित किया क्योंकि नाजीवाद तथा फासीवाद का प्रभाव वहाँ बढ़ता जा रहा था। सरकारी एवं गैर-सरकारी सहयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय-शिक्षा संस्था को विकसित किया गया ताकि विद्यार्थियों का आदान-प्रदान एवं विदेशी-अध्ययन सम्भव हो सके।

संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने की दृष्टि से विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही पासपोर्ट तथा वीसा के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाकर पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। विकासशील देशों में प्रशिक्षित मानव-शक्ति का पर्याप्त महत्त्व होता है, इसलिए वहाँ पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा राजनीति में महत्त्वपूर्ण रूप से भाग लिया जा सकता है। जो विद्यार्थी अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे राजनीति को पर्याप्त प्रभावित करेगे और हो सकता है कि वे ही नेता बनें। इसी प्रकार अमेरिका के जो विद्यार्थी एवं शिक्षक विदेशों में अध्ययन कार्य में रत हैं वे भी उन लोगों पर प्रभाव डालने का पर्याप्त अवसर पाते हैं जो अपने देश में सम्मान एवं उत्तरदायित्व के पद पर हैं अथवा होंगे। सन् 1946 के पुलब्राइट कानून ने विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा तथा सन् 1948 के स्मिथ-मण्ड अधिनियम ने नेतृत्व के आदान-प्रदान का प्रवर्धन किया। इन अधिनियमों ने संघीय सरकार को सांस्कृतिक सम्बन्धों की रचना में रुचि लेने की ओर अग्रसर किया। व्यक्तिगत निकाय भी अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के आदान-प्रदान के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य करते हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका के करीब दस-पन्द्रह हजार लोग ऐसे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। इससे अमेरिका को अन्य देशों की जनता से सम्पर्क बनाए रखने का

प्रवसर प्राप्त होता है। इन अमेरिकी लोगों में से अधिकांश का सम्बन्ध सशस्त्र सेनाओं से है तथा पाँच लाख से भी अधिक लोग व्यक्तिगत उद्यमों में संलग्न हैं। प्रतिवर्ष दस लाख के लगभग अमेरिकी पर्यटक के रूप में अमेरिका से जाते हैं। इन सम्पर्कों एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से विदेश के लोगों के साथ निकटता बढ़ती है। किन्तु इसमें एक यह खतरा भी है कि जाने वाले लोगों ने अमेरिकी जीवन के उत्तम पक्ष का प्रतिनिधित्व न किया तो यहाँ की संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा नहीं किया जा सकता तथा इससे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है।

संयुक्तराज्य अमेरिका के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि विदेशों को यहाँ से प्रतिवर्ष कम कीमत की लाखों पुस्तकें विदेशों को भेजी जाती हैं।

स्टालिन की मृत्यु के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्धों का विकास हो गया है। सन् 1958 से रुस जाने वाले अमेरिकियों की संख्या लगभग दो गुनी हो गई है। इसी प्रकार अमेरिका में आने वाले रूसियों की संख्या भी बढ़ी है।

सोवियत सांस्कृतिक कार्यक्रम—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सोवियत सरकार द्वारा सांस्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए कितना खर्च किया जाता है। सन् 1953 में सोवियत सरकार इस कार्य पर दो बिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च करती थी। इसके बाद इस खर्च में वृद्धि ही हुई है। कुछ लेखकों का अनुमान है कि सोवियत संघ इस कार्य पर जितना धन व्यय करता है उतना शायद सभी देशों द्वारा मिल कर भी नहीं किया जाता।

विकासशील देशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए तथा अपनी संस्कृति का निर्यात करने के लिए सोवियत सत्र, शोध कार्य, भाषा एवं अन्य विशेषीकृत प्रशिक्षणों पर धन खर्च करता है तथा प्रकाशित सामग्री वितरित करता है। सोवियत प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्य, संचार-अनुसंधान आदि के द्वारा विदेशों में सोवियत संघ का जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है वह एक शान्तिप्रिय किन्तु भक्तिसम्पन्न देश के रूप में होता है जिसने बहुत कम समय में ही अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के कारण महान् उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। सोवियत संघ में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्देशित किया जाता है तथा जहाँ वे चाहे वही उनको ले जाया जाता है।

सोवियत संघ में राष्ट्रों का एक मैत्री विश्वविद्यालय (Friendship of Nations University) स्थापित किया गया है जो मास्को विश्वविद्यालय से अलग है। यहाँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के युवकों को रूसी भाषा विज्ञान, कला एवं साम्यवाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इन मन्त्रों के माध्यम से यह भाशा की जाती है कि जब ये युवक अपने देश को वापस लौटेंगे तो साम्यवाद के हित में कार्य करेंगे। अनेक अमेरिकी शिक्षा-शास्त्रियों ने जब व्यक्तिगत रूप से उच्च सोवियत शिक्षा-शास्त्रियों से बातें की तो उनको यह विश्वास हो गया कि सोवियत संघ विकासशील देशों से अमेरिका को पूरी तरह

निकासना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो गया है कि उदार प्रजातन्त्र अपने सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रसार करें तथा विदेशों से आने वाले छात्रों के साथ अधिक नम्रता एवं शिष्टता का व्यवहार करें। यह एक चुनौती है जिसका सामना करना जरूरी हो गया है।

राजनीतिक युद्ध (Political Warfare)

मानव-सम्पत्ता के प्रभाव से ही 'युद्ध' समाज की एक अभिन्न विशेषता बना हुआ है। पामर तथा पकिंस के शब्दों में "शान्ति तो एक अल्पकालीन सन्धि के समान है जिसमें विचारधारा का प्रत्येक समर्थक अपने लिए उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने के हेतु दूसरे को धोखा देने को तत्पर है।" युद्ध केवल सेना द्वारा हथियारों से रणभेद में ही नहीं लड़े जाते। युद्ध के कई रूप होते हैं। उदाहरण के लिए— (1) मनोवैज्ञानिक युद्ध (Psychological Warfare), (2) राजनीतिक युद्ध (Political Warfare), (3) सैनिक युद्ध (Military Warfare) आदि।

राजनीतिक युद्ध का अर्थ (Meaning of Political Warfare)

राजनीतिक युद्ध का अर्थ किसी सुनिश्चित शब्दावली में व्यक्त करना कठिन है। इतिहास के उदाहरणों द्वारा ही यह भली प्रकार जाना जा सकता है कि इस प्रकार की नीति अथवा कार्यक्रम अपनाने पर अमुक देश राजनीतिक युद्ध का कर्त्ता माना जा सकता है। इसमें कोई राष्ट्र सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता, लेकिन शक्ति के किसी न किसी रूप का प्रयोग अवश्य होता है। युद्ध का निहितार्थ यह है कि विपक्षी को कोई बात स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। सैनिक-बल से ऐसा करने पर उसे हम सैनिक युद्ध की सजा देते हैं, लेकिन कूटनीति, प्रचार आदि द्वारा भी राष्ट्र को इस प्रकार विवश किया जा सकता है। जब हम प्रचार, कूटनीति, आर्थिक दबाव आदि का प्रयोग इस रूप में करें कि दूसरा देश हमारी नीतियों को मानने के लिए विवश हो जाए तो यह प्रक्रिया राजनीतिक युद्ध कहलाएगी। राजनीतिक युद्ध की असफलता प्रायः सैनिक युद्धों में परिणत हो सकती है।

राजनीतिक युद्ध के अर्थ को विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से व्यक्त करने की चेष्टा की है। स्ट्राउज-हुप एवं पासनी ने लिखा है, मूक्षम रूप में "राजनीतिक युद्ध एक व्यवस्थित क्रिया, अधिकांशतः गुप्त स्वभाव की है जो बिना शक्ति अथवा सैनिक अधिकार के दूसरे राज्य की नीतियों को प्रभावित और निर्देशित करती है।"¹ पामर तथा पकिंस के शब्दों में, "सामान्यतः युद्ध को छोड़कर इरामे (राजनीतिक युद्ध में) वे साधन शामिल किए जाते हैं जिनका किसी विशेष शत्रु या शत्रुओं को निर्बल करने के लिए प्रयोग किया जाता है।"² इन परिभाषाओं की विवेचना से यही स्पष्ट होता

1 *Strausz-Hupe and Passony* : International Relations, p. 422.

2 *Palmer and Perkins* : op cit., p. 125.

है कि राजनीतिक युद्ध भी राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का एक प्रमुख साधन है। इसका उद्देश्य पहले शत्रु को कमजोर बनाना, उसके मनोबल को क्षीण करना और शत्रु अथवा विरोधी राज्य में अव्यवस्था फैला कर उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। सामान्यतः ये ही कार्य कूटनीति, प्रचार और अन्न माधनो के होते हैं, तथापि अपनी प्रकृति और स्वरूप में ये राजनीतिक युद्ध से भिन्न हैं।

सामान्य प्रचार को हम राजनीतिक युद्ध की सजा नहीं देते, लेकिन प्रचार का उद्देश्य यदि विरोधी राज्य को निर्बल बनाना, डराना या घमकाना अथवा अपनी नीति मानने के लिए विवश करना है तो वह राजनीतिक युद्ध का अंग बन जाता है। इसी प्रकार सामान्य कूटनीति भी राजनीतिक युद्ध के अन्तर्गत नहीं आती, पर ज्योंही कूटनीति का प्रयोग उपर्युक्त उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है तो वह भी राजनीतिक युद्ध की परिधि में आ जाती है। सारांश में कूटनीति या प्रचार या आर्थिक उपग्रह आदि को राजनीतिक युद्ध की परिधि में तभी लिया जा सकता है जबकि उनका उद्देश्य या परिणाम विवशकारिता हो। कौनसी क्रिया सामान्य है अथवा राजनीतिक युद्ध का अंग है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि नाकाबन्दी (Embargo) आर्थिक स्रोतों के सुरक्षण के लिए की गई है तो यह सामान्य क्रिया है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य विरोधी राज्य को आर्थिक वस्तुओं से वंचित रखकर दुर्बल बनाना है तो यही क्रिया राजनीतिक युद्ध के अन्तर्गत गिनी जाएगी।

राजनीतिक युद्ध सैनिक युद्ध छिड़ने से समाप्त नहीं हो जाता, अपितु युद्ध काल में प्रचार, कूटनीति, आर्थिक साधन सभी राजनीतिक युद्ध के माधन बन जाते हैं और युद्ध में राष्ट्रीय हित के पक्ष में सहायक होते हैं। मन् 1962 के चीनी आक्रमण और जू 1965 तथा 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण में राजनीतिक युद्ध के इस स्वरूप का परिचय हम भली प्रकार पा चुके हैं।

राजनीतिक युद्ध के साधन (Devices of Political Warfare)

राजनीतिक युद्ध के विभिन्न साधनों को समय और परिस्थिति के अनुसार अपनाया जाता है। इस दिशा में कुछ प्रमुख साधन ये हैं—

1. विरोधी पक्षों में घम फैलाने और फूट डालने के लिए प्रचार का आश्रय लिया जाता है। विरोधी पक्ष में फूट पड़ जाने से वह दुर्बल हो जाता है जिसका लाभ दूसरे पक्ष को मिल सकता है।
2. विरोधी समुदाय को आतंकित अथवा भयग्रस्त करने वाला प्रचार किया जाता है। कभी-कभी अनावश्यक रूप से आतंकित होकर विरोधी पक्ष भुक्त जाता है अथवा अचानक ही युद्ध का आश्रय ले बैठता है। अतः इस प्रकार के प्रचार को मोक्ष विचार कर काम में लाना चाहिए।
3. शत्रु-देश में रहने वाले प्रतापस्थकों को समर्थन देकर अपने पक्ष में किया जाता है और विरोधी पक्ष को कमजोर बनाने की चाल खेनी जाती है। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध नागाओं को आश्रय और प्रोत्साहन देने की नीति में यही

चात थी। किसी देश के अल्पसंख्यक समुदायों का पक्ष लेकर सरकार के सुचारु-संचालन में भी बाधा डाली जा सकती है। लेकिन ऐसी सम्भावना लोचनान्वित प्रणाली वाले देशों में ही हो सकती है, सर्वाधिकारवादी साम्यवादी देशों में नहीं।

4. दूसरे राज्यों को निर्बल करने वाले आर्थिक साधनों को अपनाया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत-पाक युद्ध के समय अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने के लिए आर्थिक सहायता बन्द कर दी थी।

5. दूसरे राज्य के राजनीतिक अपराधियों को सुरक्षण देना, दूसरे राज्यों में गुप्तचर-गतिविधियों में वृद्धि करना आदि भी राजनीतिक युद्ध के प्रमुख साधन हैं। अमेरिका और रूस की गुप्तचर मशीनरी के कारनामों का मण्डाफोड अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पाठकों के लिए कोई छिपी बात नहीं है।

6. क्रान्ति को प्रोत्साहन देना राजनीतिक युद्ध का बड़ा प्रभावशाली साधन है। साम्यवादी देश इस साधन को बड़े सुव्यवस्थित और कारगर ढंग से प्रयोग में लाते हैं। पाकिस्तान ने भी सन् 1965 में योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठिए भेजकर भारत अधिकृत कश्मीर में क्रान्ति कराने की चाल चली थी और रेडियो से प्रसारित भी करा दिया था कि कश्मीर में क्रान्ति हो गई है। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल व्यर्थ रही क्योंकि कश्मीर की जनता सच्चे अर्थों में भारतीय नागरिक है जिनमें बग़ावत या क्रान्ति के जोते भड़काने में कोई पाकिस्तानी चाल रफ़्त नहीं हो सकती। क्रान्ति का कुछ इसी प्रकार का तरीका साम्यवादी चीन ने इण्डोनेशिया में अपनाया था और सुकार्नो-सरकार को उलटने का पड़ग्न रखा था, तथापि उसके ये इरादे सफल नहीं हो सके।

7. दूसरे राज्य की विरोधक निर्वासित सरकार को अपने देश में बढने देना, दूसरे राज्यों में राजनीतिक हत्याएँ कराना, आर्थिक तोड़-फोड़ की नीति अपनाना, शक्ति का प्रदर्शन करना आदि भी राजनीतिक युद्ध के प्रमुख साधन हैं।

इन सभी साधनों का प्रयोग राज्य अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए करते हैं, तथापि इनका प्रयोग सामान्यतः मित्र देशों के साथ नहीं किया जाता।



राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन : साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव- उपनिवेशवाद एवं युद्ध राष्ट्रीय नीति के एक साधन के रूप में

(Economic Instruments for National Policy:
Imperialism, Colonialism, Neo-Colonialism,
and War as an Instrument of National Policy)

“साम्राज्यवाद ऐसी नीति के अनुगमन अथवा समर्थन अथवा उसकी मौन स्वीकृति को कहते हैं जिसका लक्ष्य किसी राष्ट्र के नियन्त्रण-क्षेत्र अथवा साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक सीमाओं से बाहर स्थित नए प्रदेशों या अधीनस्थ क्षेत्रों की प्राप्ति द्वारा विस्तृत करना या उसके शासन को अन्य मानव-जातियों तक फैलाना है।”

—वेम्सटर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के जिन साधनों का उल्लेख पिछले अध्याय में हो चुका है, उनके अतिरिक्त आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा युद्ध भी प्रमुख साधन हैं। आर्थिक साधन और युद्ध की उपेक्षा करना तो प्रायः किसी राष्ट्र के लिए सम्भव नहीं है, तथापि वर्तमान युग में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद अनर्थ उपेक्षणीय बन गए हैं—विशेषकर एशिया और अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों के लिए।

राष्ट्रीय नीति के लिए आर्थिक साधन

(Economic Instruments for National Policy)

प्राधुनिक युग में कोई भी राज्य पूर्णतया आत्म-निर्भर होने का दावा नहीं कर सकता। एक देश की आर्थिक स्थिति दूसरे देशों की भी न्यूनाधिक रूप से प्रभावित करती है और इस प्रकार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी देश अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण करता है जिसका उद्देश्य अन्तर्गत राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि करना होता है। आर्थिक नीतियों के विभिन्न रूपों को सामान्य रूप से आर्थिक साधनों (Economic Instruments) की मंजा दी जाती है।

आर्थिक साधन : अर्थ और महत्त्व (Economic Instruments : Meaning and Importance)

पामर एवं पकिंस ने आर्थिक साधनों को परिभाषित करते हुए लिखा है, “राष्ट्रीय उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है—चाहे वह दूसरे राज्यों को हानि पहुँचाने के लिए हो अथवा नहीं—वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन मानी जाती हैं।”¹ पंडलफोर्ड एवं लिंकन के अनुसार, “विदेश-नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, प्रत्यक्ष या संयुक्त रूप से, कोई भी आर्थिक क्षमता संस्था अथवा तकनीक आर्थिक साधन है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है वे आर्थिक (उदाहरणार्थ कच्चे माल की प्राप्ति अथवा निर्यात-व्यापार में वृद्धि), राजनीतिक (अल्पविकसित राज्य में विकास अथवा व्यवस्थित परिवर्तन), सैनिक (अड्डों की प्राप्ति) अथवा मनोवैज्ञानिक (अन्य राष्ट्रों की नीति के प्रति सद्भावना अथवा सहायता) हो सकते हैं।”²

उपर्युक्त परिभाषाओं से आर्थिक साधनों के दो पहलू स्पष्ट हैं—एक तो वे राष्ट्रीय उद्देश्यों की अभिवृद्धि के साधन हैं और दूसरे वे आर्थिक नीति के साधन हैं। राष्ट्रीय उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, जैसे—राज्य के निवासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, निर्यात में वृद्धि, नए बाजारों की प्राप्ति, देश में उपलब्ध आर्थिक साधनों और स्रोतों की सुरक्षा, कच्चा माल प्राप्त करना, युद्ध की तैयारी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि। आर्थिक नीति के साधनों के रूप में ये इस प्रकार हैं—आयात कर, कम मूल्य पर निर्यात-कर, आर्थिक सहायता आदि। इन सभी का प्रयोग राष्ट्रीय हितों के संवर्द्धन और विदेश-नीति के प्रभावशाली सहायक तत्वों के रूप में किया जाता है। आर्थिक साधनों के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए वर्नान वान डायक (Vernon Van Dyke) का कथन है—“अर्थशास्त्र (आर्थिक साधन) केवल प्रभावशाली ही नहीं बल्कि एक साधक-भूमिका का भी निर्वाह करते हैं। आर्थिक साधन विदेश-नीति के निर्धारक ही नहीं बल्कि विदेश-नीति के साधक भी हैं। एक राज्य आर्थिक कारणों से किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न कर सकता है अथवा ऐसी आर्थिक विधियों को स्वीकार कर सकता है जिनसे किन्हीं भी कारणों पर आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।”³

आर्थिक साधनों के अर्थ और महत्त्व को स्पष्ट करने वाले इस विचार को ही पंडलफोर्ड एवं लिंकन ने सारांश में इस प्रकार व्यक्त किया है, “आर्थिक स्रोत शक्ति-प्रयोग के साधन हैं। इस प्रकार वे विदेश-नीति के साधक हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं की बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता के फलस्वरूप आर्थिक साधन राष्ट्रीय सम्बन्धों में अधिक महत्त्वपूर्ण हो रहे हैं।”

1 *Palmer and Perkins* : op. cit., p. 132.

2 *Padelford and Lincoln* : op. cit., p. 205.

3 *Vernon Van Dyke* : op. cit., p. 91.

आर्थिक लक्ष्यों का उनके साधनों के साथ और साधनों का उनके लक्ष्यों के साथ समायोजन अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का एक सर्वाधिक जटिल पहलू है। ये जटिलताएँ एक तो इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि स्वतन्त्र दुनिया के देशों में गैर-सरकारी पहलू आर्थिक क्रिया का संचालनकारी तत्त्व है। गैर-सरकारी पहलू हमेशा मूल्यों एवं लाभ से प्रभावित होती है और इसलिए वह सुरक्षा, कल्याण एवं विकास के राष्ट्रीय सन्ध्यों तथा नीतियों के अनुरूप भी हो सकती है और नहीं भी। राष्ट्रवाद की शक्तिशाली सत्ताएँ, जिनके द्वारा देशों के बीच अनेक संधि पंदा किए जा रहे हैं, परम्परागत आर्थिक लक्ष्यों से मिश्रित हो जाते हैं।

आर्थिक सम्बन्धों की दुनिया अनेक विरोधों से पूर्ण है। प्रत्येक राज्य एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करता है जो उसके स्वयं के हितों के अनुरूप हो। दूसरी ओर उसे अन्य राज्यों के साथ भी सहयोग करना पड़ता है जो उसके सर्वश्रेष्ठ आह्वक होने हैं और शक्तिशाली प्रतियोगी भी। इसके अनिश्चित आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्य अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देने हैं क्योंकि उनको परिवर्तन की दिशाएँ चुननी होती हैं। राज्यों के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध इतने अधिक तथा व्यापक होते हैं कि वे अन्य सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कुल संख्या से अधिक होते हैं। कभी-कभी इन आर्थिक सम्बन्धों की राष्ट्रवाद एवं सुरक्षा की भावनाओं से प्रभावित होना पड़ता है।

आर्थिक शक्ति विवाद की घटनाओं को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती है। एवं कमजोर अर्थ-व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है और साम्यवाद के लिए अनुकूल भूमि तैयार करती है। किसी भी देश के आर्थिक मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। आर्थिक दृष्टि से जो महान् प्रतिद्वन्द्वी हैं वे भी आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से एक-दूसरे की अर्थ-व्यवस्था की मजबूती पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्तराज्य अमेरिका के अनेक निगम ये चाहेंगे कि ग्रेट-ब्रिटेन के समुद्र पार के व्यापार को वे स्वयं सम्भाल लें, किन्तु संयुक्तराज्य अमेरिका यह भी सहन नहीं कर सकता कि उसका मित्र ग्रेट-ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाए।

संयुक्तराज्य अमेरिका की आर्थिक शक्ति द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से ही उसकी शक्ति का प्रधान स्रोत रही है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि संयुक्तराज्य अमेरिका इसलिए महाशक्ति बन सका क्योंकि उसके पास अणुशक्ति थी। किन्तु अणुशक्ति भी अमेरिका को केवल इसलिए प्राप्त हो सकी थी क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न था। संयुक्तराज्य अमेरिका अधिकांश देशों का सबसे बड़ा ग्राहक है और सबसे बड़ा व्यापारी है। अमेरिका की आर्थिक शक्ति ने ही उसे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों का नेतृत्व प्रदान किया है। इसकी आर्थिक शक्ति साम्यवाद के विरुद्ध स्वतन्त्र दुनिया के देशों को सैनिक सहायता देने का आधार रही है। संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा विदेश-नीति के जिन साधनों को अपनाया जाता है उन सभी का समर्थन मुख्य रूप से आर्थिक-व्यवस्था करती है। यही कारण है कि सरकारी

अधिकारी कई बार यह तर्क देते हैं कि आर्थिक मन्दी देश की सुरक्षा के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी कि साम्यवाद की प्रत्यक्ष चुनौती ।

एक देश विशेष की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था विश्व की घटनाओं को प्रभावित करती है । बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति विदेश-नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक स्रोत प्रदान करती है । योजनाओं में जब सफलता प्राप्त होनी चनी जाती है तो एक देश उन साधनों का प्रचार कर सकता है जिनको उसने प्रयुक्त किया था । आर्थिक सम्बन्धों के आधार पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है ।

आर्थिक शक्ति को राष्ट्रीय सैनिक शक्ति एवं कुल राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का मूलभूत आधार-स्तम्भ कहा जाता है । आज के युग में मानव-शक्ति, सैनिक शक्ति का उतना महत्त्वपूर्ण भाग नहीं है जितना पहले कभी था । आज की सैनिक शक्ति अधिकतर तकनीकी उद्योग एवं सरकारी वित्त पर आधारित है । घरेलू आर्थिक सस्याएँ एवं साधन-स्रोत विदेशी मामलों में एक राज्य की नीतियों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं । अनेक राज्य उस समय तक पर्याप्त सैनिक शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि दूसरे राज्यों के उद्योगों का समर्थन प्राप्त न कर लें । वे ऐसे समर्थन के बिना बड़े संघर्षों को नहीं चला सकते ।

आर्थिक साधनों के निर्धारक तत्त्व

(Determinants of Economic Instruments)

प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों (Domestic Economic Policies) पर प्रतिबन्धों अथवा स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था करता है तथा विदेशों के साथ आर्थिक सम्बन्धों का नियमन करता है । ऐसा करते समय स्वाभाविक रूप से एक देश का व्यवहार अनेक तत्वों से प्रभावित होता है ।

सर्वप्रथम तो आर्थिक क्षेत्र में दूसरे देश को सुविधा देते समय या प्रतिबन्ध लगाते समय प्रत्येक देश पर उसकी विचारधारा एवं आदर्शों का प्रभाव रहता है । उदाहरण के लिए, साम्यवादी देश में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण रहता है किन्तु पूंजीवादी प्रजातन्त्रों में स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था होती है जबकि भारत जैसे मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाते वाले देश साम्यवादी और पूंजीवादी देशों के बीच का मार्ग अपनाते हैं ।

एक देश के आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्त्व है उसका 'राष्ट्रीय स्वार्थ या हित' । पामर तथा पकिंस (Palmer and Perkins) का कहना है कि नियन्त्रण और स्वतन्त्रता तो ऐसी नीतियाँ हैं जो प्रत्येक राष्ट्र द्वारा उनके राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर अपनायी जाती हैं ।¹

आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप को निर्धारित करने वाला तीसरा तत्त्व है—उन दो राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों का रूप । यदि वे सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं तो एक देश अपने आन्तरिक विकास एवं कल्याण के लिए ऐसी नीतियाँ अपनाएगा जो दूसरे देश

के हितों के लिए घातक न हो। किन्तु यदि उन देशों के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण न होकर परस्पर शत्रुतापूर्ण हैं तो वह देश ऐसी आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर सकता है जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से दूसरे देश को हानि पहुँचाना हो।

चौथा तत्त्व है दूसरे देशों का प्रभाव। उदाहरण के रूप में रोडेशिया पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों पर ब्रिटेन के रुख को लिया जा सकता है। ग्रेट-ब्रिटेन के रुख को देख कर लगता था कि वह इन प्रतिबन्धों का हृदय से समर्थन नहीं करता किन्तु विश्व-जनमत के प्रभाव से उसने रोडेशिया को तेल न भेजने की नीति को अपना लिया। दूसरे देश के प्रभावों को मानने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह कि है आज विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी सीमा तक दूसरे देश पर आश्रित रहता है और दूसरा तर्क यह है कि प्रत्येक देश को कुछ चीजों का आयात और कुछ चीजों का निर्यात करने की आवश्यकता रहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जीवन की प्रकृति

(The Nature of International Economic Life)

राष्ट्रों के आर्थिक सम्बन्धों का इतिहास 19वीं शताब्दी के साथ प्रारम्भ होता है। इस काल में अनेक कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला तथा पर्याप्त मात्रा में एक देश द्वारा आयात व निर्यात प्रारम्भ हो गया। इन कारणों में उल्लेखनीय हैं जैसे—तकनीकी शक्ति के कारण होने वाला औद्योगिक विकास अमेरिकी जालिन, जनसंख्या में वृद्धि तथा औद्योगिक क्रान्ति और उसके कारण लोगों द्वारा देशान्तरीकरण (Migration) आदि।

19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा का बोलबाला था। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जीवन पर इस विचारधारा का प्रभाव पड़ा और यह सोचा जाने लगा कि आयात तथा निर्यात पर यदि राज्य का नियन्त्रण कम से कम रखा जाएगा तो इससे दोनों ही पक्ष (निर्यात एवं आयात) लाभान्वित होंगे, किन्तु व्यवहार में यह विचारधारा अधिक कारगर सिद्ध न हो सकी और राज्य का थोड़ा बहुत नियन्त्रण रहा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जब वस्तुओं के आयात और निर्यात की परम्परा का शीर्गणेश हुआ तब प्रत्येक देश यह प्रयत्न करने लगा कि वह अपने देश के आयात और निर्यात के बीच सन्तुलन स्थापित करे ताकि उसे विदेशों में घन न भेजना पड़े। लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशों में घन नगाया जाने लगा। विदेशों में घन लगाने के दो तरीके थे। एक तरीके के अनुसार तो पूंजी मिल, कारखाने आदि खोलने में लगाई जाती थी जहाँ उत्पादन द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सके। दूसरा तरीका यह था कि वहाँ अथवा उसके किसी भाग को श्रृंखला दे दिया जाए।

प्रथम विश्वयुद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। युद्ध के परिणामस्वरूप जो परिस्थितियाँ पैदा हुईं उनके कारण प्रारम्भ में तो यह प्रयाग किया गया कि उम्मी अर्थ-व्यवस्था को वापस रखा जाए जो युद्ध से पहले थी, किन्तु यह व्यवस्था बदलनी हुई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। फलतः राष्ट्रों को विश्व-व्यापी आर्थिक-मंदी (Economic Depression) का सामना करना पड़ा। पहले

राज्यों द्वारा आर्थिक जीवन में जो निषेधात्मक रुख अपनाया जाता था उसे अब छोड़ दिया गया। इसके म्यान पर आर्थिक मामलों में राज्य के प्रतिबन्ध बढ़ गए और राज्य ही समस्त आर्थिक सम्बन्धों का नियमन करने लगा। इस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) का जन्म हुआ जो घागे जाकर द्वितीय विश्व-युद्ध के कारणों की शृंखला में तिरोहित हो गया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक मन्दी के कारण व्यक्तिवादी अर्थ-व्यवस्था का स्थान समाजवादी अर्थ-व्यवस्था ने ले लिया। पामर तथा पकिस ने ठीक ही लिखा है कि "एक राष्ट्र जब राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण लगाता है तो उसे चाहे या अनचाहे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रतिबन्ध लगाने पड़ते हैं।"

जब व्यापार पर प्रतिबन्ध नग जाते हैं तो व्यापार का क्षेत्र एव आकार सीमित रह जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ। दो विश्व-युद्धों के बीच के समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र निरन्तर सीमित होता गया। सन् 1933 के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन आया, किन्तु इस परिवर्तन का कारण यह था कि अधिकांश देशों द्वारा पुनः शस्त्रीकरण किया जा रहा था और सभी बड़ी शक्तियों का सैनिक बजट बहुत बढ़ गया था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व की अर्थ-व्यवस्था स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गई। एक ओर साम्यवादी देश हैं जहाँ आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) का प्राधान्य है और दूसरी ओर पूँजीवादी प्रजातन्त्र हैं जो अपेक्षाकृत स्वतन्त्र-विश्व-व्यापार के समर्थक हैं। वर्तमान विश्व की अर्थ-व्यवस्था का इतिहास इन दो प्रमुख समुदायों के बीच के मौलिक विरोध एवं संघर्ष की कहानी है। एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित-साधन के आर्थिक हथियारों का अध्ययन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है।

आर्थिक साधनों के प्रकार

(Kinds of Economic Instruments)

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आर्थिक साधन अपनाए जाते हैं जिन्हें संयुक्त रूप में पामर तथा पकिस ने आर्थिक शस्त्रागार (Economic Arsenal) का नाम दिया है। इस शस्त्रागार के आयुधों का प्रयोग केवल सरकार ही नहीं करती बल्कि गैर-सरकारी रूप से व्यक्ति भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इन आर्थिक दवावों का उपयोग किमी आर्थिक लक्ष्य की अपेक्षा मुख्यतः राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये सभी साधन परस्पर इतने सम्बन्धित हैं कि एक को अपनाने पर दूसरे को अपनाना आवश्यक बन जाता है। सभी साधनों का महत्व परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ज्ञान्तिकालीन स्थिति में जो साधन उपयोगी रहते हैं, युद्धकाल में उनका महत्व प्रायः नहीं रहता और युद्धकालीन उपयोगी साधन शान्तिकाल में अपनी उपयोगिता खो देते हैं।

वर्तमान काल में एक देश द्वारा अपनी राष्ट्रीय नीति के लिए जिन विभिन्न प्रकार के आर्थिक साधनों का उपयोग किया जाता है, वे मुख्य रूप से निम्न हैं—

1. शुल्क लगाना (The Tariff)—बाहर से आयातित प्रत्येक देश से निर्यातित माल पर लगाए जाने वाले कर को चुँगी शुल्क कहते हैं अर्थात् इसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात-निर्यात से है। सामान्यतः निर्यातित सामान पर कर नहीं लगाया जाता। पर जब आयात शुल्क लगाया जाता है तो उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं—राज्य की आय में वृद्धि करना, विदेशी उद्योगों से स्वदेशी उद्योगों की रक्षा करना अर्थात् उन्हें संरक्षण देना, दूसरे राज्यों की तुलना में अपने राज्य की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना, विलासिता की वस्तुओं में आयात को हतोत्साहित कर देश में ही आवश्यक नागरिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, आयात घटाकर विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखना एवं बदले की भावना पूरी करना अर्थात् यदि दूसरे देश ने किसी देश के माल पर शुल्क लगा दिया हो तो वह देश भी उस देश से आने वाले माल पर वंसा ही शुल्क लगा दे। ऊँचे शुल्क का परिणाम सर्वदा ही ऊँचा शुल्क होता है, अतः जब कोई भी देश शुल्क की दीवार लॉध जाता है तो उसका प्रभाव अनेक देशों पर भी पड़ता है।

एक देश शुल्क या अन्य प्रतिबन्धित नीतियों द्वारा जब स्वयं को दूसरे देशों की कीमत पर सम्पन्न बनाना चाहता है तो यह 'पड़ोसी को भिखारी बनाओ' (Beggars my-neighbour) नीति कहलाती है वास्तव में शुल्क किसी भी देश के पास एक ऐसा अर्थिक अस्त्र है जिससे वह दूसरे देश को नुकसान पहुँचा सकता है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स का प्रयोग (The Use of International Cartels)—विहटलेसी (Whittlesy) के अनुसार "कार्टेल एक से या एक जैसे ही स्वतन्त्र उद्योगों की संस्था है जिसे प्रतियोगिता पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखने के लिए स्थापित किया जाता है।" जब इस संस्था के सदस्य अलग-अलग देशों के होते हैं अथवा विदेशों में व्यापार करते हैं तो यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेती है। कार्टेल्स का मुख्य तत्त्व विभिन्न व्यापारिक संगठनों के बीच एक समझौता है जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को कार्टेल्स के सदस्यों के पक्ष में प्रभावित करना होता है। कार्टेल्स बाजारों को नियमित करते हैं। इनका प्रयत्न रहता है कि बाजार में किसी का एकाधिकार स्थापित न हो जाए। कार्टेल्स केवल विक्रेताओं के हितों के संरक्षक होते हैं, वे उपभोक्ताओं से कोई सरोकार नहीं रखते। कार्टेल्स संगठन में राज्य-संगठन भाग ले सकती हैं तथापि वे प्रायः ऐसा नहीं करती। कार्टेल्स मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं—(1) मूल्य निर्धारित करने वाले, (2) उत्पादन को सीमित करने वाले, एवं (3) विक्रय के प्रदेशों को विभाजित करने वाले।

कार्टेल्स का प्रयोग उन्हीं उद्योगों में प्रभावशील ढंग से हो सकता है जहाँ उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में कार्टेल-प्रथा को प्रायः उचित नहीं समझा जाता। इस व्यवस्था के विरुद्ध ये तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं—(1) यह व्यवस्था स्वामिभक्ति के विभाजन द्वारा संश्लेषित स्वार्थों को देश-भक्ति के ऊपर रखकर मुद्रा को प्रोत्साहन देती है, (2) इस व्यवस्था में उत्पादन और वितरण पर लगाए जाने वाले प्रतिबन्धों के फलस्वरूप एक देश किसी बड़े मुद्रा के लिए उपयुक्त

आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में असफल रहता है, (3) कार्टेल-संस्थाएँ गुप्तचर-अभिकरण का काम करती हैं, (4) कार्टेल द्वारा विदेशों में पूँजी लगाने की व्याज-दर निश्चित कर देने से कोई अन्य देश वहाँ पूँजी लगाने में असमर्थ रहता है, (5) कार्टेल्स पूँजीवादी एकाधिकारवादी व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, एवं (6) यह व्यवस्था सर्वाधिकारवादी राज्यों का विशेष साधन है जिसका अन्त किया जाना चाहिए।

व्हिटलेसी ने कार्टेल्स का पक्ष लेते हुए स्वीकार किया है कि इनसे यदि राष्ट्र-वाद का सपोषण होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है। कार्टेल-व्यवस्था गुप्तचर इसलिए नहीं मानी जा सकती कि इसके द्वारा दी जाने वाली सूचनाएँ एकपक्षीय नहीं होती। व्हिटलेसी के शब्दों में, "कार्टेल अपने आप में कोई दोष नहीं है, यह तो एक साधन है जिसका प्रयोग अच्छे-बुरे दोनों ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। यह मानना अनुचित है कि इस व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को निर्बल बनाया जाता है।"¹

3. अन्तर्संस्कारी वस्तु-समझौता (Inter-Governmental Commodity Agreement)—यदि किसी एक वस्तु का उत्पादन एक से अधिक देशों में होता है तो उत्पादक राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का निराकरण करने और उस वस्तु-विशेष के मूल्य के विश्व-बाजार में स्थिर करने के लिए उत्पादक राज्यों के बीच जो समझौता होता है उसे अन्तर्संस्कारी वस्तु समझौता कहते हैं। यह व्यवस्था प्रायः इन मुख्य उद्देश्यों से प्रेरित होती है—(1) विभिन्न राज्यों में वस्तु-विशेष के उत्पादन की व्यवस्था, (2) उत्पादक राज्यों के हितों की रक्षा, (3) उत्पादक राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की समाप्ति, एवं (4) वस्तु-विशेष से लाभ-प्राप्ति का मूल्य निर्धारण। स्मरणीय है कि ये समझौते कृषि और खनिज-उत्पादन पर ही होते हैं, औद्योगिक उत्पादन पर नहीं। विविध राज्यों में औद्योगिक वस्तुओं के प्रतिमानों में बहुत भिन्नता होती है जबकि यह भिन्नता कृषि एवं खनिज-उत्पादन में बहुत कम पाई जाती है। ये समझौते सरकारी के मध्य ही होते हैं, कार्टेल्स की भाँति निजी उद्योग-पतियों द्वारा नहीं।

अन्तर्संस्कारी समझौतों की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इन्हें केवल संकटकाल का सामना करने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में जहाँ अनुशाल पद को बनाए रखा जाता है ये स्थायी आश्रय बन जाते हैं। जब ये समझौते अपने इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। इस प्रकार इन समझौतों को आर्थिक युद्ध के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

4. कम मूल्य पर निर्यात करना (Dumping)—यदि कोई देश घरेलू बाजार में प्रचलित मूल्यों से भी कम मूल्यों पर किसी वस्तु का निर्यात करता है तो इस व्यवस्था को 'डम्पिंग' कहते हैं। प्रायः इन उद्देश्यों के लिए इस व्यवस्था का आश्रय लिया जाता है—(1) देश की आवश्यकता से अधिक एकत्रित या उपलब्ध वस्तु-भण्डार को कम करने के लिए, (2) किसी वस्तु की माँग बाजार में घट गई हो तो

उसकी कीमत घटाकर मन्दी के बाजार को उठाने के लिए, (3) यदि कोई दूसरा देश प्रतियोगी हो तो प्रतियोगी देश के मूल्य से कम मूल्य में वस्तु बेचकर उसकी प्रतियोगिता समाप्त करने के लिए, (4) विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए, एवं (5) घनी राज्य द्वारा किसी निर्धन राज्य को अपने प्रभाव में लाने के लिए। महाशक्तियाँ कम मूल्य पर निर्यात की नीति अपनाकर पहले तो निर्धन राज्यों के प्रति उदार होने का स्वाँग भरती है और फिर उन पर राजनीतिक रूप से छा जाने का प्रयत्न करती हैं।

5 पहले से ही माल की खरीद (Pre-empture Buying) — इस व्यवस्था के अन्तर्गत दूसरे राज्यों के सामान को शत्रु के हाथों में पड़ने से पूर्व ही खरीद लिया जाता है। उद्देश्य यह रहता है कि शत्रु-राज्य के पास वह सामान किसी भी राज्य से न पहुँचने पाए। सामान खरीदते समय उनके व्यापारिक पक्ष अर्थात् लाभ-हानि पर ध्यान नहीं दिया जाता। पॉल एन्जिग (Paul Einzig) ने लिखा है कि “ज्योही द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ त्योंही जर्मनी ने अपने एजेंटों को आज्ञा दी कि बाल्टिक और दक्कान क्षेत्रों में से किसी भी कीमत पर वे अधिक से अधिक माल की खरीददारी कर डालें। दूसरी ओर ग्रेट ब्रिटेन ने इस सम्बन्ध में पैसे और परेशानी की ओर ध्यान दिया। फलतः वह असफल रहा।”¹ पूर्व-क्रय प्रणाली का शत्रु-देश पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। युद्धों अथवा संघर्षों के समय आर्थिक युद्ध का यह एक महत्वपूर्ण अस्त्र है।

6. व्यापार और भुगतान समझौते (Trade and Payment Agreements) — ये समझौते दो देशों के बीच भी हो सकते हैं और दो से अधिक देशों के बीच भी। इन समझौतों द्वारा अन्य राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से पृथक्-सा कर दिया जाता है। इस अर्थ में इनको राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है।

7. शत्रु सम्पत्ति पर नियन्त्रण (Control of Enemy Assets) — प्रत्येक देश में कुछ विदेशी राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं जिनकी उस देश में सम्पत्ति उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है। लेकिन जिस राज्य में वे रह रहे हैं उसे उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति अपहरण करने का अधिकार होता है। शत्रु-राष्ट्र या अतिविरोधी देश के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करने के लिए सम्पत्ति-अपहरण की इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

सम्पत्ति-अपहरण की परम्परा बहुत पुरानी है। वर्साय की सन्धि के अधीन यह स्पष्ट व्यवस्था की गई थी कि मित्रराष्ट्र अपने अधिकार-क्षेत्रों में बसने वाले सभी जर्मन राष्ट्रीयता वाले लोगों की सम्पत्ति का अपहरण कर सगने हैं और जर्मनी का यह उत्तरदायित्व माना गया कि वह ऐसे लोगों की क्षतिपूर्ति करे। द्वितीय महायुद्ध के समय डेनमार्क और नार्वे पर जर्मनी का हमला होने पर अमेरिका ने वहाँ के लोगों की सम्पत्ति को हस्तगत कर लिया ताकि निरपराध तटस्थ लोगों के हितों की रक्षा की जा सके; पर इसका एक बड़ा कारण हिटलर की सम्भावित प्राप्ति से बचन रखना था।

8. ऋण तथा अनुदान (Loans and Grants) —राज्यों के आपसी सम्बन्धों को बढ़ाने में अनुदान और ऋण प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ऋण किसी देश के आर्थिक विकास के लिए लिया जाता है जिसमें अन्तर्निहित लक्ष्य उस देश के साथ भेदोक्ति बढ़ाना होता है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऋण और उपहारों की भाँट में उस देश को अपने राजनीतिक प्रभाव में लेना होता है। ऋण लेने वाले देश को ऋण के प्रभाव से अपनी नीतियाँ बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ना है। राजनीतिक रूप से अनुचित प्रभाव डालने की नीति के रूप में ऋण और उपहार आज महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं। भारत-पाक संघर्ष के समय ब्रिटेन ने भारत को अस्वास्थ्य भेजना बन्द कर दिया था क्योंकि भारत सरकार पाकिस्तान सम्बन्धी ब्रिटिश रवियों की विरोधी थी। अमेरिका ने सन् 1971 के युद्ध के बाद भारत को आर्थिक सहायता देना इसलिए बन्द कर दिया था क्योंकि भारत अमेरिकी दृष्टिकोण से सहमनन था। यदि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करें तो अमेरिका, रूस आदि महाशक्तियाँ ऋण और अनुदान के साधन का बहुत अधिक प्रयोग करती रही हैं। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के नाम पर मार्शल योजना, ट्रूमैन सहायता सिद्धान्त, पारस्परिक सहायता योजना आदि के रूप में अपनी ऋण और उपहार नीति का प्रयोग किया जिसे रूस ने साम्राज्यवाद के ही एक रूप की संज्ञा दी। भारत के विरोध में पाकिस्तान के प्रति इसी प्रकार की नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

9. विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control) —विनिमय नियन्त्रण की आवश्यकता प्रायः तब होती है जब किसी देश के विदेशी विनिमय की माँग पूर्ति से अधिक हो। विनिमय नियन्त्रण द्वारा कोई देश अपनी पूँजी को विदेश जाने से रोक सकता है, अपनी मुद्रा की अधिक कीमत स्थिर कर सकता है, आयात और निर्यात के बीच सन्तुलन ला सकता है, राष्ट्रीय धन्य-व्यवस्था को पृथक् कर घरेलू योजनाओं की सुरक्षा कर सकता है। वर्तमान में विनिमय-नियन्त्रण की व्यवस्था लगभग सभी अविकसित राज्यों द्वारा की जाती है। भारत ने इस व्यवस्था का बड़ी दक्षता से प्रयोग किया है।

10. आर्थिक सहायता (Subsidies) —द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त विदेशी आर्थिक सहायता राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का एक बहुत ही प्रभावशील अस्त्र बन गया है। युद्धोत्तर युग में इसके तीन मुख्य रूप रहे हैं—(1) युद्ध-पीडित देशों को राहत और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना, (2) नवोदित राष्ट्रों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए सहायता देना, एवं (3) साम्यवादी दबाव या आन्तरिक उपद्रवों आदि का सामना करने के लिए सम्बन्धित देशों को आर्थिक सहायता देना।

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त अमेरिका ने विदेशी आर्थिक सहायता को साम्यवाद-अवरोध-नीति के रूप में बड़े जोर शोर से अपनाया है। एशिया और अफ्रीका में नवोदित स्वतंत्र राज्यों को आर्थिक विकास के लिए प्रचुर विदेशी सहायता देने की नीति रूस, अमेरिका आदि महाशक्तियों ने व्यापक रूप में अपनाई है। इसके मूल में

यह महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य निहित है कि सहायता पाने वाला देश सहायता देने वाले देश के प्रभाव में रहे, कहीं विरोधी श्रेणी में न चला जाए। पश्चिमी जर्मनी, जापान, चीन और किसी सीमा तक भारत ने भी आर्थिक सहायता के शक्तिशाली साधन को अपनाया है। नवोदित बंगला देश को भारत सरकार ने उदारतापूर्वक आर्थिक एवं अन्य आवश्यक सहायता इसीलिए दी थी कि वह अपनी विनष्ट अर्थ-व्यवस्था का पुनरुद्धार करे, भारत-बंगला देश की मैत्री में वृद्धि हो और बंगला देश को चीन आदि भारत विरोधी राष्ट्रों के सामने आर्थिक सहायता के लिए हाथ न पसारना पड़े।

आर्थिक सहायता का अभिप्राय केवल अनुदान आदि से होना भ्रामक है। आर्थिक सहायता का अर्थ वस्तुतः बहुत व्यापक है जिसके अन्तर्गत ये बातें सम्मिलित हैं—(1) शस्त्रास्त्रों की सहायता, (2) विकास-ऋण, (3) तकनीकी सहायता, एवं (4) अनुदान। ये सभी प्रकार की आर्थिक सहायता लचीली भी हो सकती है और कठोर भी अर्थात् इनके साथ जो शर्तें आदि जुड़ी होती हैं वे काफी उदार भी हो सकती हैं और अनुदार या अपेक्षाकृत कड़ी भी। विकास ऋण अधिक या मामूली ब्याज पर कम या अधिक समय के लिए दिया जा सकता है। यदि कोई राज्य भुगतान करने की स्थिति में न हो या अन्य कोई राजनीतिक कारण हो तो ऋणदाता राष्ट्र सहायता का कुछ भाग या पूरा भाग अनुदान में ही परिवर्तित कर सकता है। यह बहुत कुछ सहायता देने वाले और लेने वाले राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, हाल के वर्षों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वाशिंगटन पैकिंग-पिण्डी गठबन्धन तेजी से विकसित हुआ है और अमेरिका तथा चीन ने पाकिस्तान को बहुत-सा ऋण अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया है। दोनों ही देश पाकिस्तान पर अपने प्रभाव के आकांक्षी हैं, अतः उसे आर्थिक सहायता देने के मामले में यदि प्रतिस्पर्धा हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। भारत के विरुद्ध जो दुरभिसन्धि चल रही है, उससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता मुपरिचित हैं।

विदेशी आर्थिक सहायता केवल मानवीय व सहयोगपूर्ण आदि भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं दी जाती। आज के युग में वे अधिकांशतः राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती हैं। यह एक ऐसा साधन है जो सहायता देने वाले राज्य की उदारता प्रकट करता है जबकि वास्तव में सहायक राज्य किसी न किसी राजनीतिक उद्देश्य में प्रेरित होकर ही सहायता के लिए आगे आता है और इसमें अपने राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि देखता है। अमेरिका जब एशियाई राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देता है तो उसके मूल में दो तीन राजनीतिक उद्देश्य अवश्य निहित होते हैं—सहायता पाने वाले राज्य पर साम्यवादी दबाव प्रभावी न हो सके, वह राज्य अमेरिका के प्रभाव-क्षेत्र में आ जाए, आर्थिक सहायता के माध्यम से अमेरिकी राजनीतिक तत्त्व उस देश में प्रवेश कर जाएँ आदि। रूसी आर्थिक सहायता के मूल में भी कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य छिपे होते हैं। यदि आर्थिक सहायता देना राज्य विशेष के हित में न हो तो वह आर्थिक सहायता देगा ही क्यों? हाँ अकाल, बाढ़, भुमभूरी आदि मकड़ों के समय मानवीय भावनाओं से प्रेरित होकर आर्थिक सहायता अवश्य दी जाती है, पर इसमें

भी राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि की आकांक्षा धिरी रहती है। रूस, अमेरिका जैसे सम्पन्न राज्यों को आशंका रहती है कि यदि संकटग्रस्त देश को कोई सहायता न दी गई तो विश्व-जनमत के सामने वे बदनाम हो जायेंगे।

विदेशी आर्थिक सहायता के माध्यम से राज्य अपने हितों में अभिवृद्धि किस प्रकार करते हैं, इसका कुछ आभास हमें निम्नविवक्षित बातों से मिलता है—

1. जब एक राज्य दूसरे राज्य को सामान आदि के रूप में सहायता देता है तो सहायक राज्य के उद्योगों और उत्पादन को प्रोत्साहन देता है।

2. सहायता देने के लिए अधिक उत्पादन किया जाता है जिससे आर्थिक मन्दी का भय नहीं रहता।

3. सहायता लेने वाला राज्य सहायता देने वाले राज्य के राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव क्षेत्र में आ सकता है। सामान आदि भेजने के साथ ही सहायता देने वाला राज्य अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी सहायता पाने वाले राज्य में विशेष सक्रिय कर देता है।

4. सहायक राज्य में अधिक उद्योग-धन्यों के चलते रहने से वहाँ के लोगों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर सुलभ होते हैं।

5. सहायता देने वाले राज्य के पास जब किसी वस्तुओं का प्रचुर भण्डार एकत्रित हो जाता है या कुछ ऐसी वस्तुएँ बड़ी मात्रा में एकत्र हो जाती हैं जो गुणों की दृष्टि से गिरी हुई हों तो उनको सहायता प्राप्त करने वाले राज्य को दे दिया जाता है। इससे एक ओर तो सहायता देने वाले राज्य का निकम्मा माल खप जाता है और दूसरी ओर उसे आर्थिक व राजनीतिक लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका जो खाद्यान्न भारत को देता है उसकी उपयोगिता अमेरिका में केवल इतनी ही है कि उसे ईंधन के रूप में जला दिया जाय या फैंक दिया जाए।

6. जब सहायता देने वाला राज्य ऋण आदि देता है तो उसे व्याज प्राप्त होता है। ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था का तो यह प्रमुख आधार रहा है और वर्तमान अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का भी यह एक मुख्य आधार है।

7. सहायता प्राप्त करने वाला राज्य सामान आदि को सहायक राज्य के जहाजों में ही ले जाता है जिससे माल ढोने आदि में भी सहायक राज्य के व्यापारियों को लाभ प्राप्त होता है। अमेरिका में तो कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि इस प्रकार का लगभग आधा माल अमेरिकी जहाजों से ही जाएगा।

उपर्युक्त सभी कारणों से विदेशी आर्थिक सहायता राष्ट्रीय उद्देश्यों की अभिवृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। विदेशी सहायता जब तकनीकी रूप में दी जाती है तो विदेशी विशेषज्ञों को सहायता पाने वाले देश में उच्च वेतन मिलते हैं। साथ ही विशेषज्ञों के रूप में सहायक राज्य के गुप्तचर और राजनीतिक अधिकारी भी आ जाते हैं जो उस राज्य में अपना कुचक्र चलाते हैं। सारांशतः यह कहना होगा कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उदीयमान देशों के सम्बन्ध में साम्यवादी और पश्चिमी शक्तियों के बीच जो प्रतिद्वन्द्विता है तथा साम्यवादी गुट में नेतृत्व का जो

आपसी संघर्ष है उसने विदेश नीति के इस साधन (आर्थिक सहायता) की अवहेलना करना महाशक्तियों के लिए अव्यावहारिक बना दिया है।

11. कोटा और लाइसेंस (Quotas and License)—जब सरकार आयात पर सीधा नियन्त्रण रखना चाहती है तो वह कोटा-व्यवस्था का आश्रय लेती है। इसके अधीन एक देश से या विभिन्न देशों से आने वाले माल की एक सीमा निश्चित कर दी जाती है। कोटा-व्यवस्था इसलिए अपनायी जाती है कि देश के उत्पादकों की रक्षा की जा सके और देश का आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक न हो पाए। निर्यात-व्यापार पर कोटा व्यवस्था का प्रयोग प्रायः युद्धकाल में ही किया जाता है क्योंकि यह आशंका रहती है कि जिस देश को माल निर्यात किया जा रहा है वह उसी माल को कहीं शत्रु देश के लिए निर्यात न कर दे। आयात पर और भी अधिक नियन्त्रण लगाने के लिए लाइसेंस-व्यवस्था अपनायी जाती है। इसके अधीन कोई भी दूसरा देश जब कभी निर्यात करना चाहेगा तो उसे इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस देते समय देश अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखेगा। कोटा और लाइसेंस प्रणाली भी प्रभावी आर्थिक अस्त्र हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह में बाधा डाल देते हैं।

12. वार्ज सूची (Black Lists)—इस साधन के अधीन एक देश द्वारा ऐसी सूची प्रसारित की जाती है जिसमें उन राष्ट्रों के नाम होते हैं जिनके साथ व्यापार का बहिष्कार करना हो। सूचीबद्ध नामों के साथ देश का कोई व्यक्ति या संस्था व्यापारिक सम्बन्ध नहीं रख सकती। सूचीबद्ध लोगों की सम्पत्ति का भी उस देश द्वारा प्रायः अग्रहण कर लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि वार्ज सूची किसी राज्य के सम्बन्ध में नहीं बनायी जाती अपितु केवल व्यक्तिगत उद्योगों और व्यक्तियों पर ही लागू होती है।

13. मूल्य निर्धारण (Valorization)—जब सरकार किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाती है तो इसे 'मूल्य निर्धारित करना' कहा जाता है। यहाँ इसका अर्थ केवल यह है कि उस वस्तु को खरीद कर अपने पास रख ले अथवा उसके उत्पादन को घटा दे। अन्तर्सरकारी वस्तु-समझौतों के प्रचलन के फलस्वरूप अब इस साधन का महत्त्व बहुत कम हो गया है।

14. घाटबन्दी (Embargo)—यदि कोई राज्य दूसरे राज्य को कुछ वस्तुओं या सम्पूर्ण व्यापार से वंचित रखना चाहता है तो वह अपने व्यापारियों और व्यापारिक संस्थाओं पर दूसरे राज्य से लेनदेन या व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा देता है। घाटबन्दी का प्रयोग सामान्य रूप से किसी राज्य को दण्डित करने अथवा उसने प्रति अपनी नाराजगी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ सन् 1959 से चीन के प्रति अमेरिका ने घाटबन्दी की नीति का अनुसरण किया था जिसे अब प्रायः समाप्त कर दिया गया है।

जिन विभिन्न आर्थिक साधनों का उल्लेख किया गया है उन्हें समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न देश अपनी-अपनी सामर्थ्य और शक्त के अनुरूप

उपयोग में लाते हैं ताकि उनके राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और मर्यादित सम्बन्धन हो सके। राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन केवल वे ही नहीं जिन्हें ऊपर गिनाया गया है वरन् समयानुसार सरकारें और भी नए रूपों में अपना लेती हैं।

आर्थिक युद्ध (Economic Warfare)

एक देश अपने आर्थिक साधनों का प्रयोग कर जब दूसरे विरोधी राज्य की सम्भावित एवं वास्तविक शक्ति को कम करने का प्रयास करता है तो उसे हम प्रायः आर्थिक युद्ध का नाम देते हैं। इस प्रकार के संघर्ष परम्परागत रूप से होते रहते हैं, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। इस सम्बन्ध में क्लासविज का यह कहना अत्यन्त युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है कि “शान्तिकाल में अपने शत्रु को कूटनीति और व्यापार द्वारा निःशस्त्र बना दो, तब उसे तुम युद्ध के मंशान में आसानी से जीत सकोगे।” प्रत्येक राज्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में समझाते-बुझाने से लेकर हिसात्मक साधनों तक प्रत्येक कार्यवाही को अपना सकता है। आर्थिक तकनीक तथा प्रसाधन इन तरीकों के बीच में ही स्थान रखते हैं। आर्थिक साधन जैसे किराी की सहायता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वैसे किसी के विरुद्ध भी काम में लाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) एक देश में विनिमय की साख को आर्थिक सुधारों से संयुक्त कर सकता है, किन्तु यदि एक देश से इस प्रकार की साख को रोक दिया जाए तो उस देश के विरुद्ध आर्थिक दबाव कहाँ-कहाँ और स्पष्ट रूप से आर्थिक युद्ध की कोटि में आएगा। आर्थिक दबाव एक देश की आर्थिक स्थिति एवं सामर्थ्य को कमजोर बना देते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व दुनिया के देश आर्थिक दबावों के प्रभाव को बहुत महत्व देते थे। सन् 1935 में राष्ट्रसंघ ने इटली के विरुद्ध आर्थिक दबावों का उपयोग किया क्योंकि उसने इथियोपिया के विरुद्ध आक्रमण कर दिया था, किन्तु दबाव प्रभावहीन रहे। ऐसी ही प्रतिबन्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सन् 1951 में नाम्बियादी चीन के विरुद्ध लगाए गए थे जबकि उसने कोरिया पर आक्रमण किया था। ये दोनों ही प्रतिबन्ध प्रभावहीन रहे। ग्रेट-ब्रिटेन ने सन् 1965 में रोडेसिया पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए और संयुक्तराज्य अमेरिका तथा अन्य कुछ देशों ने उनको सहयोग दिया। केवल कामजी रूप से बेरोजगारी उस समय तक प्रभावहीन रहती है जब तक कि इसका समर्थन करने वाले एक या अधिक राज्य उस देश के महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतों के स्वामी न हों, जैसे—तेल, हथियार, खाद्य सामग्री आदि।

आर्थिक दबाव किसी देश के विरुद्ध केवल सीमित प्रभाव ही डाल पाते हैं। ये केवल छोटे समय तक ही प्रभावशाली रहते हैं और बाद में मित्रराष्ट्रों में अनेक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। सम्बन्धित देश यह सोचते हैं कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। व्यापारिक लेन-देन के सन्तुलन को प्राथमिकता दी जाती है और इन दबावों की प्रभावशीलता को रद्द करने की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे इन दबावों का प्रभाव कम हो जाता है। पेंडलकोर्ड तथा लिंकन का यह कथन उपयुक्त है कि शान्तिकालीन आर्थिक युद्ध की प्रकृति सम्बद्ध रहनी चाहिए,

इसमें पर्याप्त कूटनीति एवं समायोजन की आवश्यकता है तथा यह देखना जरूरी है कि बढ़ते हुए मनमुटावों का साभ हो रहा है या नहीं।

साम्राज्यवाद (Imperialism)

समाजवाद की भांति ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की तुलना एक ऐसे टोपे से की जा सकती है जिसे हर कोई पहन लेता है, अतः उसका रूप, आकार और अर्थ सुनिश्चित नहीं रह गया है। साम्राज्यवाद—उपनिवेशवाद कभी बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता था और साम्राज्यवादी देशों को विश्व-कल्याण का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज के लोकतान्त्रिक युग में साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी या विस्तारवादी कहलाने से हर एक भय खाता है, इसे एक आरोप समझा जाता है। जो देश वास्तव में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं वह भी स्वयं को साम्राज्यवादी कहलाना पसन्द नहीं करते। साम्राज्यवाद के स्वरूप, उद्देश्य, साधन और परिणामों के बारे में विचारकों में काफी मतभेद हैं तथापि इस बात को प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि यह राष्ट्रीय हित की प्राप्ति का एक प्रभावशाली साधन रहा है और आज भी है।

साम्राज्यवाद क्या है ?—अर्थ की समस्या

(What is Imperialism ?—

The Problem of the Meaning)

साम्राज्यवाद के वास्तविक अर्थ को सुनिश्चित शब्दों में बताना बठिन है। इसका प्रयोग इतने व्यापक रूप में किया जाता है कि इसके अन्तर्गत लगभग प्रत्येक प्रकार की विस्तारवादी प्रक्रिया आ जाती है। पामर एव पेरिंस के अनुसार, “साम्राज्यवाद की विवेचना, निन्दा और रक्षा की जा सकती है और इसके लिए प्राणों का उत्सर्ग तक किया जा सकता है, लेकिन इसकी ऐसी परिभाषा नहीं की जा सकती जो सामान्यतया सभी को स्वीकार्य हो।”¹ साम्राज्यवाद का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए भिन्न-भिन्न है, तथापि हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं के आधार पर साम्राज्यवाद की प्रकृति को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं।

रेमण्ड ब्यूएल (Raymond Buell) के शब्दों में, “एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार पर प्रत्येक अन्यायोचित माँग, प्रत्येक आक्रामक मुद्दा साम्राज्यिक मुद्दा कहलाता है। साम्राज्यवाद एक ऐसा शब्द है जिसके अन्तर्गत वास्तव में सभी प्रकार के पाप आ जाते हैं।”²

मॉरिज जूलियस बोन (Moritz Julius Bonn) ने लिखा है कि “साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य एक साम्राज्य अथवा एक ऐसे विशाल राज्य का निर्माण, संगठन और अनुरक्षण करना होता है जो न्यूनाधिक

1 Palmer and Perkins : op. cit., p. 158.

2 Raymond Buell : International Relations, p. 305.

भिन्न प्रकार की राष्ट्रीय इकाइयों के संयोग से बना हो और एक केन्द्रीकृत इच्छा के अधीन हो।"¹

चार्ल्स बियर्ड (Charles A. Beard) के मतानुसार, "साम्राज्यवाद वह होता है जिसमें एक देश की सरकार और कूटनीतिक मशीनरी दूसरी जाति के लोगों के प्रदेशों (Territories), रक्षित राज्यों (Protectorates) तथा प्रभाव-क्षेत्रों (Spheres of Influence) को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है और औद्योगिक, व्यापारिक एवं धन लगाने के व्यवसायों को बढ़ाने का कार्य करती है।"²

सी डी बर्न्स (C. D. Burns) ने साम्राज्यवाद के प्रशासनिक और वानूनी रूप पर बल देते हुए लिखा है कि "विविध देशों और जातियों पर एक ही प्रकार के कानून तथा शासन की व्यवस्था का नाम ही साम्राज्यवाद है।"³ उन्होंने साम्राज्यवाद को विश्व-सरकार की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम माना है। उनका कथन है कि वह क्षेत्रीय राष्ट्रीयता के दोषों को दूर कर उससे ऊपर उठता है। साम्राज्यवाद क्षेत्रीय राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता के बीच की स्थिति है। बर्न्स के विचारों से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अधिकांश विद्वान् सहमत नहीं हैं। शूमा ने लिखा है कि चाहे कितने ही बहाने बनाएँ और नैतिकता का चाहे कितना ही ढोल पीटें, लेकिन सत्य तो यह है कि अधीन देशों पर शक्ति और हिंसा के बल पर विदेशी राज्य स्थापित करना साम्राज्यवाद है।

एच. बी. वेल्स (H. G. Wells) के अनुसार, "एक राष्ट्रीय राज्य का विश्व व्यापक बनने के लिए प्रयत्नशील होना ही साम्राज्यवाद है।" पार्कर मून (Parker T. Moon) के शब्दों में, "साम्राज्यवाद का अर्थ गैर यूरोपीय जातियों पर उनसे सर्वथा भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के शासन से है।"⁴ मॉर्गन्थो (Morgenthau) ने विशाल धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति, बड़े प्रदेश की प्राप्ति, दूसरी जातियों पर शासन आदि विशेषताओं को गौर मानते हुए विचार प्रस्तुत किया है कि एक देश द्वारा अपने राज्य की सीमाओं से बाहर शक्ति का विस्तार ही साम्राज्यवाद है। एक अन्य विचारक बुखारिन (N. L. Bukharin) का कहना है कि साम्राज्यवाद में दूसरे देशों को जीतने का प्रयास निहित रहता है, किन्तु दूसरे देशों को जीतने की नीति को ही हम साम्राज्यवाद नहीं कह सकते।⁵ शुम्पीटर (Schumpeter) के अनुसार साम्राज्यवाद का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तथा इसके उद्देश्यों की सुनिश्चित परिभाषा भी नहीं की जा सकती।

1 *Mortiz Julius Bonn* : "Imperialism", *Encyclopaedia of the Social Sciences*, VII, 605—Quoted by *Palmer and Perkins* : op. cit., p. 158.

2 *Charles A. Beard* : *American Foreign Policy in the Making, 1932-1940, A Study in Responsibilities*, p. 113 n.

3 *C. D. Burns* : *Political Ideals*, p. 154.

4 *Parker T. Moon* : *Imperialism and World Politics*, p. 33.

5 *N. L. Bukharin* : *Imperialism and World Economy*, p. 114.

साम्राज्यवाद से सम्बन्धित विभिन्न परिभाषाओं के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस शब्द का प्रयोग विद्वानों द्वारा अपने-तकों अथवा अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अलग-अलग अर्थों में किया गया है और इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि साम्राज्यवाद शब्द अपना सही अर्थ खो बैठा है। आज किसी भी देश को आप 'साम्राज्यवादी' कह सकते हैं यदि उसकी विदेश नीति आपके देश की विदेश नीति के विपरीत पड़ती हो। पामर एवं पर्किन्स ने साम्राज्यवाद के निम्नलिखित तत्वों तथा उद्देश्यों का उल्लेख किया है ¹

- (i) "साम्राज्यवाद के गैर-आर्थिक आकर्षण हो सकते हैं।
- (ii) साम्राज्यवाद का कार्यक्रम सीमित हो सकता है। यह आवश्यक ही नहीं है कि एक बृहद् साम्राज्य की स्थापना ही हो।
- (iii) साम्राज्यवाद का अभिप्राय एक जाति का दूसरी जाति पर ही अधिकार नहीं है, यह एक जाति के अन्तर्गत ही स्थापित हो सकता है।
- (iv) साम्राज्यवाद व्यवस्थित ढंग से ही स्थापित हो सकता है और अव्यवस्थित ढंग से भी।
- (v) साम्राज्यवाद के मुख्य परम्परावादी तत्व हैं : राजनीतिक अधिकार, आर्थिक प्रभुत्व, सत्ता का प्रयोग आदि।

मून (Parker T. Moon) ने 'साम्राज्यवाद' शब्द को औपनिवेशिक विस्तार का समानार्थक माना है। किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आखिर औपनिवेशिक विस्तार शब्द से आपका क्या अभिप्राय है क्योंकि विस्तार के रूप सैनिक, आर्थिक सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि कई होते हैं।

मॉर्गेन्थो (Morgenthau) इस बात से शुब्ध है कि 'साम्राज्यवाद' शब्द का निश्चिदक प्रयोग अपनी सीमा लीज गया है और इसे किसी भी विदेश-नीति से जोड़ दिया जाता है, केवल इसीलिए कि वह विदेश-नीति आपकी नीति के विपरीत है। अंग्रेजों से घृणा करने वाले सन् 1960 के ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ठीक उसी तरह एक वास्तविकता के रूप में प्रदर्शित करेंगे जिस तरह कि वे सन् 1940 अथवा 1941 में करते थे। रूस से घृणा करने वाले रूस की विदेश-नीति को साम्राज्यवादी कहेंगे स्वयं रूस द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों को 'साम्राज्यवादी लक्ष्य' से प्रेरित होकर लड़ने वाले 'राष्ट्र' मानता रहा किन्तु सन् 1941 में जर्मनी द्वारा आक्रमण कर दिए जाने पर जो युद्ध लड़ना पड़ा वह उसकी दृष्टि में साम्राज्यवाद-विरोधी युद्ध बन गया। संयुक्तराज्य अमेरिका के आलोचकों के लिए हर स्थान पर 'अमेरिकी साम्राज्यवाद' एक पारिभाषिक शब्द बन गया है और शका तब और भी बड़ जाती है जब कुछ विशेष आर्थिक तथा राजनीतिक पद्धतियों, आर्थिक गुटों आदि को बिना प्रभेद किए साम्राज्यवादी विदेश-नीतियों से संबद्ध कर दिया जाना है। वस्तुतः हालत यह हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति या राज्य, जो किसी राष्ट्र की विदेश

नीति के प्रतिरिक्त कोई अन्य विदेश-नीति अपनाता है, प्रतिपक्षी द्वारा साम्राज्यवादी मान लिया जाता है।¹

मॉर्गेंथो का कहना है कि साम्राज्यवाद का सही अर्थ जानने के लिए यह आवश्यक है कि उससे सम्बन्धित कुछ भ्रान्तियों का निवारण कर लिया जाए— (1) प्रथम, प्रत्येक विदेश-नीति, जिसका उद्देश्य एक राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना है, आवश्यक रूप में साम्राज्यवाद का प्रदर्शन नहीं कही जा सकती। केवल उसी नीति को साम्राज्यवादी कहा जा सकता है जिसका लक्ष्य यथापूर्व-स्थिति (Status-quo) को नष्ट-भ्रष्ट करना है। (2) द्वितीय, वे लोग भी भ्रम में हैं जो पहले से ही स्थित साम्राज्य की रक्षा करने वाली विदेश-नीति को साम्राज्यवादी कहते हैं। वर्तमान साम्राज्य की सुरक्षा, उसके स्थायित्व और सन्तुलन के सपोपण को 'साम्राज्यवाद' की सजा देना उचित नहीं कहा जा सकता। मॉर्गेंथो का विचार है कि साम्राज्यवाद की प्रकृति गत्यात्मक (Dynamic) होती है जिसके द्वारा एक नया साम्राज्य स्थापित किया जाता है। पूर्वस्थित साम्राज्य की रक्षा करने वाली नीति से इस 'गत्यात्मक प्रकृति' का आभास नहीं होता, अतः इस नीति को हम रूढ़िवादी कह सकते हैं न कि साम्राज्यवादी। साम्राज्य (Empire) की रक्षा और सुदृढ़ता (Consolidation) एक चीज है तथा साम्राज्यवाद दूसरी। दोनों के बीच भारी अन्तर रहता है। सन् 1942 में चर्चिल ने जब 'ब्रिटिश साम्राज्य के समापन-समारोह में सभापतित्व करने से इंकार कर दिया था' तो वह एक साम्राज्यवादी की हैसियत से नहीं बल्कि विदेशी मामलों में एक रूढ़िवादी की हैसियत से बोल रहा था, साम्राज्य की यथा-स्थिति के संरक्षक के रूप में (A Defender of the Status-quo of Empire) बोल रहा था।

मॉर्गेंथो के अनुसार जब हम साम्राज्यवाद सम्बन्धी भ्रान्तियों से दूर रहकर वास्तविक स्थिति पर विचार करेंगे तो हमें साम्राज्यवाद का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। पर आधुनिक युग में केवल औपनिवेशिक साम्राज्य की ही चर्चा नहीं की जानी बल्कि आर्थिक साम्राज्यवाद की भी बात बही जाती है और जब हम साम्राज्यवाद से सम्बन्धित आर्थिक सिद्धान्तों पर विचार करते हैं तो साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति फिर अस्पष्ट बन जाती है।

साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धान्त (Economic Theories of Imperialism)

मॉर्गेंथो के अनुसार साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धान्त तीन पृथक् विचारधाराओं से विकसित हुए हैं। पहली मार्क्सवादी विचारधारा (The Marxist Theory of Imperialism) है जो पूंजीवाद को मुख्य बुराई तथा साम्राज्यवाद को उसी का आवश्यक या सम्भावित परिणाम मानती है। दूसरी, उदारवादी विचारधारा (The Liberal Theory of Imperialism) है जिसके प्रमुख प्रतिनिधि

है ए. हॉब्सन। इस विचारधारा के अनुसार साम्राज्यवाद पूँजीवाद का परिणाम न होकर वास्तव में पूँजीवादी व्यवस्था के कुछ असन्तुलन का परिणाम है। मार्क्सवाद की भाँति ही उदारवादी विचारधारा भी साम्राज्यवाद की जड़ अतिरिक्त उत्पादन और पूँजी में माननी है जिसके लिए विदेशी बाजारों की खोज अनिवार्य हो जाती है। फिर भी हॉब्सन तथा उसकी विचारधारा के अनुसार यह अतिरिक्त उपज खरीदने की शक्ति के गलत सन्तुलन का परिणाम मात्र है, उसका हल घरेलू बाजार के विकास में निहित है जो क्रय-शक्ति में वृद्धि और आवश्यकता से अधिक बचत की समाप्ति आदि आर्थिक सुधारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साम्राज्यवाद के प्रति एक घरेलू विकल्प में विश्वास ही उदारवाद को मार्क्सवाद से पृथक् करता है। तीसरी विचारधारा 'दानवी सिद्धान्त' (The 'Devil Theory' of Imperialism) है। यह सिद्धान्त उपर्युक्त दोनों सह-सिद्धान्तों के विपरीत बहुत ही भिन्न बौद्धिक स्तर पर संचालित होता है। इस सिद्धान्त को साम्यवादी अपनाते हैं और आज तो यह उनके प्रचार का एक मुख्य हथियार बन गया है। इसे 'न्ये कमेटी' (Nye Committee) का आधिकारिक दर्शन' कहा जा सकता है, जिसने संयुक्तराज्य-सीनेट की ओर से सन् 1934-36 में प्रथम महायुद्ध में संयुक्तराज्य के हस्तक्षेप पर वाणिज्य व उद्योग-धन्यों के प्रभाव की खोज की थी। कमेटी की बैठकों को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, उसके कारण कुछ समय तक यह 'दानवी-सिद्धान्त' संयुक्त-राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का स्पष्टीकरण करने का मुख्य साधन बना रहा। सिद्धान्त की सरलता ने उसकी लोकप्रियता में भारी योग दिया। इसने कुछ विशेष गुटों की ओर सकेत किया जो कि स्पष्ट रूप से युद्ध में लाभ उठाते हैं जैसे युद्ध की वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगपति (हथियार बनाने वाले वर्ग) अन्तर्राष्ट्रीय बैंकर्स (बाल स्ट्रीट) आदि। चूँकि उनको युद्ध में लाभ होता है, इसलिए उनके लिए उसमें संलग्न होना स्वाभाविक है। इस प्रकार युद्ध से लाभ उठाने वाले युद्ध-प्रचारकों में बदल जाते हैं अर्थात् उन 'दानवों' में जो युद्ध की योजना बनाते हैं ताकि उससे स्वयं को धनी बना सकें। संक्षेप में, दानवी सिद्धान्त के अनुसार युद्ध के कारण जिन समुदायों या व्यक्तियों को लाभ होता है वे सदैव युद्ध को प्रोत्साहन देते रहते हैं ताकि वे स्वयं सम्पन्न बन सकें। इन युद्धों का परिणाम ही साम्राज्यवाद है।

मॉर्गन्थो महोदय के अनुसार ये तीनों ही विचारधारों एकपक्षीयता (Onesidedness) के दोष से ग्रसित हैं। 'साम्राज्यवाद' असल में एक राजनीतिक तत्त्व है और जैसा कि कुछ विचारकों का कहना है, इन विचारधारामें द्वारा इसको आर्थिक रूप देने का असफल प्रयास किया गया है।

साम्राज्यवाद सम्बन्धी कुछ निष्कर्ष
(Some Conclusions about Imperialism)

जब साम्राज्यवाद को किसी निश्चित परिभाषा में नहीं बाँधा जा सकता, हमें सम्बन्धित जो सिद्धान्त विकसित हुए हैं वे एकपक्षीय हैं, तो फिर साम्राज्यवाद

के स्वरूप को इसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर ही अधिक प्रबन्धी तरह समझा जा सकता है, जो निम्न प्रकार है—

1. 'साम्राज्यवाद' शब्द स्वानुमतिमूलक (Subjective) है और इसीलिए विचारक अपनी इच्छानुसार जैसा चाहते हैं इसकी परिभाषा दे देते हैं।

2 'साम्राज्यवाद' शब्द अपने विरोधी देशों की नीतियों की आलोचना करने का एक साधन बन गया है।

3. साम्राज्यवाद की कुछ अवसरगत विशेषताएँ जैसे प्राथिक लाभ का लक्ष्य, क्षेत्र का विस्तार, दूसरी जातियों पर शासन एक सुनियोजित कार्यक्रम, आदि साम्राज्यवाद के साथ रहती हैं, किन्तु साम्राज्यवाद इनके बिना भी रह सकता है।

4 साम्राज्यवाद नैतिक दृष्टि से शून्य होता है। यह राष्ट्रीय नीतियों का एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य बुरा भी हो सकता है और प्रबन्धा भी। हो सकता है कि साम्राज्यवाद के अधीनस्थ देश आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में पर्याप्त विकास करें और यह भी सम्भव है कि साम्राज्यवादी देशों द्वारा अधीनस्थ जनता का शोषण किया जाए, उसका दमन किया जाए तथा उसकी सम्यता और सस्कृति के विकास को अवरुद्ध किया जाए। पामर तथा पकिस के मतानुसार साम्राज्यवाद तो शक्ति-सम्बन्धों का उच्च और अधीनस्थ के बीच के सम्बन्धों का नाम है, नैतिकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

5. साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देने वाले तत्त्व मॉर्गेंथो के मतानुसार तीन हैं। पहला तत्त्व ये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों हैं जो युद्ध के बाद शांति स्थापनार्थ की जाती हैं तथा जिनके द्वारा युद्ध से पूर्व की स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए वर्साय की सन्धि का नाम लिया जा सकता है। दूसरा तत्त्व वह प्रयास है जो कुछ राष्ट्रों को स्थायी रूप से अधीन (Subordinate) बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रयासों की प्रतिक्रिया यह होती है कि हारा हुआ राष्ट्र अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने की कोशिशें करता है। फलतः उसकी नीति साम्राज्यवादी हो जाती है। साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देने वाला तीसरा तत्त्व कमजोर एवं राजनीतिक शक्ति से हीन राज्यों का अस्तित्व है। ऐसे राज्य शक्तिशाली राज्यों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे 'शव' द्वारा गिद्धों को आकर्षित किया जाता है। ये तीनों ही तत्त्व ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं जिनमें साम्राज्यवाद की नीतियाँ बनती, क्रियान्वित होती तथा सफल होती हैं।

साम्राज्यवाद के तीन लक्ष्य

(Three Goals of Imperialism)

मॉर्गेंथो ने लिखा है कि चूँकि साम्राज्यवाद तीन विशेष परिस्थितियों (ऊपर वर्णित) से उत्पन्न होता है, अतः साम्राज्यवाद तीन लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता है¹—

- (1) विश्व-साम्राज्य (World Empire),
- (2) महाद्वीपीय साम्राज्य (Continental Empire),
- (3) स्थानीय प्रभुता (Local Preponderance) ।

विश्व-साम्राज्य (World Empire)—साम्राज्यवाद का पहला विशिष्ट लक्ष्य सम्पूर्ण पृथ्वी के राजनीतिक रूप से सगठित प्रदेशों पर प्रभुत्व स्थापित करना होता है अर्थात् एक विश्व-व्यापी साम्राज्य की स्थापना करना । इस प्रकार के असीमित साम्राज्यवाद के असाधारण उदाहरण सिकन्दर महान्, रोम, सातवी तथा आठवी शताब्दियों में अरबों, नेपोलियन प्रथम, हिटलर आदि की विस्तारवादी नीतियों में देखा जा सकता है । जैसे कि मॉर्गन्थो ने लिखा है—इन सभी की नीतियों में विस्तार की ओर एक सामान्य प्रवृत्ति प्रकट होती है जिसकी कोई भी विवेकपूर्ण सीमा नहीं है और जो अपनी सफलताओं पर पनपती है और यदि अपने से अधिक शक्तिशाली शक्ति द्वारा रोक न दी जाए तो सम्पूर्ण राजनीतिक जगत् में विस्तार के लिए प्रवृत्त होती है । यह प्रवृत्ति उस समय तक तुष्ट नहीं हो सकती जब तक कि वही भी साम्राज्य का कोई सम्भव लक्ष्य मौजूद है । सौभाग्यवश अतीत में इस प्रकार का असीमित साम्राज्यवाद ही साम्राज्यवादी नीतियों के अन्त का कारण बनता रहा है । केवल रोम ही कुछ विशेष कारणोंवश अपवाद रहा था ।

महाद्वीपीय साम्राज्य (Continental Empire)—साम्राज्यवाद का दूसरा विशिष्ट लक्ष्य एक महाद्वीपीय सीमा के अन्तर्गत साम्राज्य स्थापित करना हो सकता है । इसे भौगोलिक रूप से निर्धारित साम्राज्यवाद (Geographically Determined Imperialism) कहा जा सकता है और इस प्रकार के साम्राज्यवाद के स्पष्ट उदाहरण हमें यूरोपीय शक्तियों की उन नीतियों में मिलते हैं जिनका लक्ष्य यूरोपीय महाद्वीप में प्रभुत्व स्थापित करना था । लुई चौदहवाँ, नेपोलियन तृतीय और विलियम द्वितीय इसके उदाहरण हैं । सन् 1850 के दशक में कैबूर की अध्यक्षता में विडमोन्ट राज्य की इटली प्रायद्वीप पर प्रभुत्व की अभिलाषा, सन् 1912 और 1913 में बल्कन युद्ध के विभिन्न भागीदारों की बल्कन प्रायद्वीप में प्रभुत्व की अभिलाषा, भूमध्य सागर को इटालियन भील बनाने का मुसोलिनी का प्रयत्न—ये सब महाद्वीपीय सीमाओं के अन्तर्गत भूगोल द्वारा निर्धारित साम्राज्यवाद के उदाहरण हैं । उन्नीसवीं शताब्दी में अमेरिकी नीति, जिसके अन्तर्गत उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पच्चे भू-भाग में शनैः-शनैः अमेरिकी विस्तार की योजना रही, पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्यतः महाद्वीप की भौगोलिक सीमाओं द्वारा निर्धारित थी, क्योंकि संयुक्तराज्य ने बनावट और मैक्सिको को अपने आधिपत्य में लाने का प्रयत्न नहीं किया यद्यपि ऐसा करने में वह निश्चय ही सफल हो सकता था । महाद्वीपीय साम्राज्यवाद इस स्थान पर स्थानीय सीमाओं के लक्ष्य द्वारा संगोषित कर दिया गया । इसी प्रकार का मिश्रित साम्राज्यवाद पश्चिमी गोलाद्ध से सम्बन्धित अमेरिकी नीति का तत्त्व बन जाता है । मुनरो सिद्धान्त ने पश्चिमी गोलाद्ध के लिए अमेरिकी शक्तियों से सम्बन्धित एक यथापूर्व-स्थिति की नीति निर्धारित कर बचाव की एक ढाल तैयार कर दी जिसके

पीछे संयुक्तराज्य उस भौगोलिक क्षेत्र में अपना स्वयं का प्रभुत्व स्थापित कर सके। परन्तु उन भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत अमेरिकी नीति स्थायी रूप से सदा साम्राज्यवादी नहीं थी।

स्थानीय प्रभुत्व (Local Preponderance)—स्थानीय साम्राज्यवाद का रूप 18वीं और 19वीं शताब्दियों की राजतन्त्रात्मक नीतियों में देखने को मिलता है। 18वीं सदी फ्रैंडरिक महान्, लुई पन्द्रहवें, मैरिया थेरसा, पीटर दी ग्रेट और कैथरीन द्वितीय इस प्रकार की विदेश-नीति की संचालक-शक्तियाँ थीं। उन्नीसवीं शताब्दी में बिस्मार्क इस प्रकार की साम्राज्यवादी नीति का उस्ताद था जिसने यथास्थित-व्यवस्था (The Status-quo) को पलट कर स्वयं निर्धारित की हुई सीमाओं के भीतर राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना का लक्ष्य बनाया है। इस प्रकार की स्थानीय साम्राज्यवादी नीति और महाद्वीपीय साम्राज्यवाद तथा असीमित साम्राज्यवाद में वही अन्तर है जो बिस्मार्क, विलियम द्वितीय तथा हिटलर की विदेश-नीतियों में था। बिस्मार्क मध्य यूरोप में जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, विलियम समस्त यूरोप में और हिटलर सम्पूर्ण जगत् में। रूसी साम्राज्यवाद के परम्परागत लक्ष्य, जैसे फिनलैण्ड, पूर्वी यूरोप, बल्कान, दारदनेल्स व ईरान पर नियन्त्रण भी स्थानीय साम्राज्यवाद के रूप में है। इस प्रकार के साम्राज्यवाद की सीमाएँ, भौगोलिक साम्राज्यवाद की तरह प्रकृति के बाह्य तथ्यों द्वारा निर्धारित नहीं होनी, बल्कि यह कई पक्षान्तरों में से स्वतन्त्रतापूर्वक चुना हुआ एक मार्ग होता है जैसे—यथापूर्व-स्थिति की नीति, महाद्वीपीय साम्राज्यवाद या तीसरा स्थानीय साम्राज्यवाद। अठारहवीं शताब्दी में तीसरा पक्षान्तर इस कारण श्रेयस्कर था, क्योंकि उस समय शक्तियों का एक जमाव ऐसा था जो एक-दूसरे के प्रायः बराबर थी और महाद्वीपीय साम्राज्यवाद के प्रयत्न को हतोत्साहित करती थी। लुई चौदहवें के अनुभव ने दर्शा दिया कि इस प्रकार का प्रयत्न कितना सफल हो सकता है और फिर 18वीं सदी का साम्राज्यवाद मुख्यतः राजाओं की व्यक्तिगत शक्ति और यश-लोत्पत्ति से संचालित होता था, न कि आधुनिक राष्ट्रवाद की जनवादी भावनाओं से। ये मान्यताएँ यूरोपीय संस्कृति की राजतन्त्रात्मक परम्पराओं के ढाँचे के अन्तर्गत संचालित होती थी जो कि राजनीतिक रंगमंच के नेताओं पर एक नियन्त्रण का कार्य करती थी। 19वीं शताब्दी में स्थानीय साम्राज्यवाद की नीति का यह चुनाव-तत्त्व बिस्मार्क की विदेश-नीति में सर्वाधिक प्रभावशाली रूप में दृष्टिगोचर होता है। सबसे पहले उसे प्रशा के उन दक्षिण पक्षी तत्त्वों के विरोध का सामना करना पड़ा जो प्रशा के लिए यथापूर्व-स्थिति के समर्थन के पक्ष में थे और बिस्मार्क की स्थानीय साम्राज्यवादी नीति को पसन्द नहीं करते थे। इस नीति के द्वारा बिस्मार्क जर्मनी में प्रशा का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहता था। जब विजयी युद्धों ने बिस्मार्क की नीति को सम्भव बना दिया तो इस नीति की रक्षा करना भी आवश्यक हो गया—विशेषकर उनसे जो कि बिस्मार्क द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करना चाह रहे थे। सन् 1890 में विलियम द्वितीय द्वारा बिस्मार्क को

पदच्युत करना इस स्थानीय साम्राज्यवाद की समाप्ति का और जर्मन विदेश-नीति में महाद्वीपीय साम्राज्यवाद की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति के प्रारम्भ का चोटक था।

साम्राज्यवाद के तीन साधन

(Three Methods of Imperialism)

मॉर्गेंथो ने लिखा है कि जिस तरह विशेष परिस्थितियोंवश तीन प्रकार का साम्राज्यवाद पनपता है और अपने लक्ष्य के अनुसार भी तीन प्रकार के साम्राज्यवाद होते हैं, उसी तरह साम्राज्यवादी नीतियों के साधनों में तीन प्रकार की विभिन्नताएँ स्थापित करनी होंगी। तदनुसार हमें निम्नलिखित तीन साम्राज्यवादों में अन्तर करना चाहिए—

- (1) सैनिक साम्राज्यवाद (Military Imperialism),
- (2) आर्थिक साम्राज्यवाद (Economic Imperialism),
- (3) सांस्कृतिक साम्राज्यवाद (Cultural Imperialism)।

मॉर्गेंथो की दृष्टि में सैनिक साम्राज्यवाद सैनिक विजय की माँग करता है, आर्थिक साम्राज्यवाद दूसरे लोगों का आर्थिक शोषण चाहता है तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का लक्ष्य एक सस्कृति को दूसरी सस्कृति द्वारा उन्मूलन करना होता है—किन्तु ये सब सर्वदा एक ही साम्राज्यवादी लक्ष्य के साधन के रूप में काम करते हैं और यह लक्ष्य होता है यथापूर्व-स्थिति को पलट देना अर्थात् साम्राज्यवादी राष्ट्र तथा उसके होने वाले शिकार के शक्ति-सम्बन्धों को पलट देना। इस लक्ष्य को या तो सैनिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक साधनों द्वारा प्राप्त किया जाता है या किसी एक ही साधन द्वारा अथवा साधनों के संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ हम इन्हीं तीनों साधनों का उल्लेख कर रहे हैं—

सैनिक साम्राज्यवाद (Military Imperialism)—साम्राज्यवाद का सबसे स्पष्ट, सबसे प्राचीन और सबसे असस्कारी रूप सैनिक विजय है। सभी युगों के महान् विजेता महान् साम्राज्यवादी भी रहे हैं। एक साम्राज्यवादी राष्ट्र के दृष्टिकोण से इस पद्धति का लाभ यह है कि सैनिक विजय के फलस्वरूप जो नए शक्ति-सम्बन्ध स्थापित होते हैं उन्हें पराजित राष्ट्र द्वारा भड़काए हुए अन्य युद्ध द्वारा ही बदला जा सकता है और इस युद्ध में सफलता की सम्भावना प्रायः उस पराजित राष्ट्र की उतनी नहीं होती जितनी कि साम्राज्यवादी राष्ट्र की होती है। लेकिन साम्राज्यवाद के सैनिक साधन के इस सबसे बड़े दोष की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि युद्ध एक जुमा है, वह जीता भी जा सकता है और हारा भी जा सकता है। एक राष्ट्र जो साम्राज्यवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध प्रारम्भ करता है, साम्राज्य प्राप्त कर उसे अपने अधीन भी रख सकता है जैसा कि रोम ने किया था अथवा वह उसे जीत कर खो भी सकता है अर्थात् दूसरों के साम्राज्यवाद का शिकार बन सकता है जैसा कि नाजी जर्मनी और जापान के मामले में हुआ। सैनिक साम्राज्यवाद वह जुमा है जो सर्वोच्च दाव के लिए खेला जाता है।

आर्थिक साम्राज्यवाद (Economic Imperialism)—मॉर्गेंथो के अनुसार आर्थिक साम्राज्यवाद कम क्रूरतापूर्ण और सामान्यतया सैनिक प्रणाली से कम प्रभावकारी है। एक विवेकपूर्ण साधन द्वारा शक्ति हथियाने के रूप में यह आधुनिक युग की उपज है। यह व्यापारिक और पूंजीवादी विस्तार के आधुनिक युग की उत्पत्ति है जिसका आधुनिक विलक्षण उदाहरण 'डॉलर साम्राज्यवाद' (Dollar Imperialism) है। इसने ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही पुर्तगाल में ब्रिटिश प्रभाव शक्तिशाली आर्थिक नियन्त्रण द्वारा समर्थित रहा है। अरब जगत् में ब्रिटिश सर्वोच्चता उन आर्थिक नीतियों का ही परिणाम थी जिन्हें 'तेल कूटनीति' (Oil Diplomacy) कहा जाता है। दो महायुद्धों के बीच फ्रांस ने जो अपना प्रबल प्रभाव रूमानिया जैसे देशों पर थोरा वह काफी हद तक आर्थिक तत्वों पर आधारित था।

जिन नीतियों को हम आर्थिक साम्राज्यवाद की सज्ञा देते हैं उनकी एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि वे साम्राज्यवादी राष्ट्र और दूसरे देशों के बीच के शक्ति सम्बन्धों की मथापूर्व स्थिति को उलट देनी हैं और ऐसा करने में प्रादेशिक विजय का नहीं, बल्कि आर्थिक नियन्त्रण का सहारा लिया जाता है। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय अमेरिका के सब प्रमुख सम्पन्न राज्य समुक्तराज्य अमेरिका के आर्थिक साम्राज्यवाद के शिकार हैं। इन राज्यों का आर्थिक जीवन प्रायः पूरी तरह समुक्तराज्य अमेरिका के निर्पात पर निर्भर है, अतः वे राज्य अधिक समय तक किसी ऐसी विदेश नीति या गृह-नीति का अनुसरण नहीं कर सकते जिसका समुक्तराज्य अमेरिका विरोध करता हो। आर्थिक साम्राज्यवाद के माध्यम से दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने या उसे कायम रखने का अनि प्रभावशाली रूप तब बहुत साफ-साफ दिखाई देता है जबकि दो प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्यवादी राष्ट्र एक-दूसरे के आर्थिक साधनों द्वारा एक ही सरकार पर नियन्त्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरणार्थ, ईरान पर नियन्त्रण के लिए रूस और ब्रिटेन के बीच प्रतिद्वन्द्विता सदियों पुरानी है जो कई बार लम्बे समय तक सैनिक साधनों द्वारा भी संचालित रही है। ग्रेट ब्रिटेन के हाथों में दक्षिण फारस का तमाम विदेशी व्यापार था, वह अदन से लेकर बिलोन्निस्तान तक सम्पूर्ण एशियायी तट पर अपने आर्थिक नियन्त्रण का दावा करता था। उसने उधर कभी भी क्षेत्रीय सम्पत्ति की अभिलाषा नहीं की। परन्तु रूस के व्यावसायिक अस्व दो रहे—या तो उसने व्यापार पर एकाधिकार चाहा या इसमें असफल रहने पर उसका निषेध किया। उसने ईरान में रेल बनाने के लिए अनिच्छा व्यक्त की और उन लक्ष्यों का प्रायः विरोध किया जिनके फलस्वरूप देश का पुनरुत्थान हो सकता था। इस प्रकार ईरान ब्रिटेन और रूस के बीच आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता का शिकार बना रहा। रूस उन पर उत्तर से दबाव डालता था तो ब्रिटेन दक्षिण से। ईरान की तरफालीन विदेश-नीति और गृह-नीति इन दो प्रतियोगी गुटों के दबावों के बीच घिसती रही। जब रूस उन आर्थिक लाभों को प्रदान करता था या उनका आश्वासन देता था जो ब्रिटेन की ओर से ईरान को नहीं मिल सकते थे अथवा जब

रूस स्वीकृत लाभों को वापस ले लेने की धमकी देता था तो रूस का प्रभाव बढ जाता था और इसी तरह विपरीत स्थिति होने पर ब्रिटेन के प्रभाव में वृद्धि होती थी। न तो रूस ने ईरान की भूमि हडपने का साहस किया और न ब्रिटेन की ही ऐसी कोई इच्छा थी। लेकिन दोनों ही ईरानी सरकार पर नियन्त्रण रखने के आकांक्षी थे, ईरान में अपने आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रसार को फलीभूत देखना चाहते थे। आज भी अमेरिका डॉलरो द्वारा एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए अनेक राष्ट्रों में अपना आर्थिक साम्राज्यवाद फैलाए हुए है। अमेरिका ने—निकसन प्रशासन ने—भारत के लिए आर्थिक सहायता का निषेध कर 'डॉलर कूटनीति' का दबाव डालना चाहा और फोर्ड प्रशासन भी पीछे नहीं रहा तथा उनके पश्चात्पूर्वी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की नीतियों में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। वर्तमान में रोनाल्ड रीगन भी उसी परिपाटी पर चल रहे हैं जो उन्हें उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों से विरासत में मिली है परन्तु विश्व के इस सर्वाधिक धन-सम्पन्न राष्ट्र को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत भीषण कठिनाइयाँ भेल सकता है लेकिन स्वाभिमान को नहीं बेच सकता, किसी के आर्थिक-राजनीतिक दबाव से नहीं झुक सकता। भारत पिण्डी-मेकिंग-वाशिंगटन गठजोड़ के कारनामों के प्रति भी सजग रहा है।

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद (Cultural Imperialism)—मॉर्गेन्यो का मत है कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद सबसे सूक्ष्म और यदि अपने आप ही (बिना सैनिक तथा आर्थिक साम्राज्यवाद का सहारा लिए) सफल हो जाए तो सबसे सफल साम्राज्यवादी नीतियों में से है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का लक्ष्य भू-क्षेत्रों की विजय अथवा आर्थिक जीवन का नियन्त्रण नहीं होता, बल्कि लोगों के मस्तिष्कों पर विजय पाकर उन्हें नियन्त्रित करना होता है ताकि उनके माध्यम से दो राष्ट्रों के बीच शक्ति-सम्बन्धों को पलट दिया जाए। यदि हम कल्पना करें कि 'अ' राज्य की संस्कृति और विशेषकर उसकी राजनीतिक विचारधारा, अपने सभी ठोस साम्राज्यवादी लक्ष्यों के साथ, 'ब' राज्य की नीतियों का निर्धारण करने वाले सभी नागरिकों के मस्तिष्कों को जीत लेती है तो हम देखेंगे कि 'अ' राज्य की विजय किसी भी सैनिक या आर्थिक साम्राज्यवादी की विजय से कहीं अधिक पूर्ण होगी। 'अ' राज्य को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए न किसी फौजी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और न आर्थिक दबाव डालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह तो 'ब' राज्य के नागरिकों को अपनी राजनीतिक विचार-पद्धति की सम्मोहन शक्ति में बाँध चुका है और इस प्रकार 'ब' राज्य ने 'अ' राज्य की इच्छा के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर दिया है—वह 'अ' राज्य की उच्चतर सत्त्वर्तिता का और उसके अधिक आकर्षक राजनीतिक दर्शन का गुनाम बन चुका है।

परन्तु यह तो एक काल्पनिक उदाहरण है। व्यवहार में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद ऐसी सम्पूर्ण विजय में बाँधी पीछे रह जाता है अर्थात् उसकी विजय इतनी 'पूर्ण' नहीं होती कि साम्राज्यवाद के अन्य माधनों का महत्त्व न रहे। आधुनिक युग में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की विशिष्ट भूमिका अन्य माधनों की महत्कारिणी है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद शत्रु को शिथिल बना देता है और इस तरह सैनिक विजय अथवा

आर्थिक प्रवेश के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण कर देता है। इसका एक प्रमुख आधुनिक उदाहरण है 'पाँचवीं पंक्ति' (The Fifth Column) और उसकी दो विलक्षण सफलताओं में से एक तो नाजी सेना की पाँचवीं पंक्ति है जिसका प्रयोग द्वितीय महायुद्ध के पूर्व और प्रारम्भ में किया गया था और जिसकी सफलता आस्ट्रिया में सबसे अधिक दिखाई देती थी। उस समय जबकि वहाँ की नाजीवादी सरकार ने जर्मन फौजों को देश पर कब्जा करने के लिए आमन्त्रित किया। नाजियों की पाँचवीं पंक्ति ने फ्रांस और नार्वे में भी काफी सफलता प्राप्त की क्योंकि वहाँ की सरकार के भीतर और बाहर अनेक प्रभावशाली नागरिक देशद्रोही बन गए। वे नाजी दर्शन और उसके अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुयायी हो गए। यह कहना अनिश्चित्यपूर्ण न होगा कि जर्मनी की सैनिक विजय से पूर्व ही ये देश अधूरे दौर पर सांस्कृतिक साम्राज्यवादी साधनों द्वारा जर्मनी के कब्जे में लाए जा चुके थे। ग्रेट-ब्रिटेन नाजी सांस्कृतिक प्रवेश के भय से हर समय चौकता रहता था और इसीलिए उसने द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में ही अपनी राज्य-सीमाओं के भीतर प्रत्येक नाजी को और उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नजरबन्द कर दिया था। वास्तव में जर्मन साम्राज्यवाद को तीव्र गति से प्रारम्भिक सफलताएँ इसीलिए मिली कि वह अपने सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार द्वारा अपनी सैनिक विजयों का मार्ग अधिक आसान बना चुका था। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के दूसरे विलक्षण उदाहरण के रूप में साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय (The Communist International) को गणना की जा सकती है और यह बात राजनीति के किसी भी साधारण छात्र तक से छिपी नहीं है कि जिस सीमा तक साम्यवादी दल किसी देश में अपना वैचारिक प्रभाव स्थापित कर लेना है उसी अनुपात में सोवियत रूस या चीन का प्रभाव उस देश में बढ़ता जाता है और जहाँ साम्यवादी दल राष्ट्रीय सरकार पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेना है वहाँ रूसी या चीनी सरकार का व्यावहारिक नियन्त्रण स्थापित हो जाता है। संयुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत रूस आदि महाशक्तियाँ जब अफ़े शियायी देशों में अपने साहित्य का विशाल माना में प्रचार-प्रसार करती हैं तो उसका एक मुख्य लक्ष्य 'सांस्कृतिक साम्राज्यवाद' का प्रसार होता है ताकि उनके राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए समुचित आधार तैयार हो जाए। कौन नहीं जानता कि अनेक अफ़े शियायी देशों के विश्वविद्यालयों में, जिनमें भारत के विश्वविद्यालय भी हैं, अमेरिकी साहित्य का साम्राज्य-सा छाया हुआ है और हमारे शिक्षा तन्त्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे पढ़े-लिखे भारतीयों की संख्या कम नहीं है जो 'तन' से हिन्दुस्तानी पर 'मन' से ईंगलिस्तानी या 'अमेरिकी' हैं। जब तक देश में इन बुद्धिजीवियों का प्रभाव व्याप्त रहेगा, और जब तक ये लोग अपने प्रभाव के बल पर विदेशी साहित्य को प्रश्रय देते रहेंगे, तब तक भारत में उस राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान नहीं हो सकता जो किसी स्वाधीन देश की जनता का 'वास्तविक आत्मबल' होना है। देश का उच्चतम नेतृत्व इस प्रवृत्ति का विरोधी है, लेकिन 'अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता' वाली कहावत चरितार्थ होनी है। यह देश के बुद्धिजीवियों का धार्मिक और राष्ट्रीय

कर्तव्य' है कि वे देश में विदेशी शक्तियों के 'सांस्कृतिक प्रवेश' के विरुद्ध शक्तिशाली ढाल का काम करें न कि उसे प्रोत्साहन दें। हाँ, यदि 'काली' चमड़ी को 'गोरी' चमड़ी बनाने का कोई नुस्खा ईजाद हो गया हो तो फिर यह मायापञ्ची करने के प्रश्न पर शायद पुनर्विचार करना पड़े।

साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (Imperialism, Colonialism and Nationalism)

साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के बीच का अन्तर इतना कम है कि प्रायः एक के लिए दूसरे का प्रयोग कर दिया जाता है। हॉब्सन (Hobson) ने साम्राज्यवाद विषयक अपनी पुस्तक में साम्राज्यवाद की जो परिभाषा दी है वह असल में उपनिवेशवाद पर अधिक लागू होती है। उनके मतानुसार, "उपनिवेशवाद अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में राष्ट्रीयता का स्वाभाविक अतिरेक (Overflow) है। इसकी परीक्षा उपनिवेशों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे अपनी सम्पत्ता को अपने नवीन सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढाल सकें।"¹ साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का ही एक रूप समझा जाता है, किन्तु यह उपनिवेशवाद की तुलना में अधिक संगठित, अधिक सैनिक, प्रत्यक्ष रूप से अधिक आक्रमणकारी तथा विभिन्न उद्देश्यों से पूर्ण होता है। इतने अन्तरो के रहते हुए भी व्यवहार में इन दोनों के बीच एक विभाजन रेखा खींचना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इन दोनों ही पदों का प्रयोग उच्च तथा निम्न का सम्बन्ध (Superior-inferior Relationship) बताने के लिए किया जाता है।

सैद्धान्तिक रूप में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद परस्पर विरोधी हैं क्योंकि साम्राज्यवाद दूसरे देशों को पराधीनता के पाश में जकड़ता है जबकि राष्ट्रीयता प्रत्येक देश को स्वतन्त्र रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। किन्तु व्यवहार में पराधीन देश स्वतन्त्र होने के बाद जब शक्तिशाली बन जाता है तो प्रायः साम्राज्य-निर्माण का स्वप्न देखना प्रारम्भ कर देता है। पराधीन राष्ट्रों में साम्राज्यवाद के प्रभाव से राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत होती है और स्वतन्त्र राष्ट्रों में राष्ट्रीयता साम्राज्यवादी भावनाओं को उकसाती है। ब्यूल (Buell) का कहना है कि "शुद्ध राष्ट्रवाद सरकारों को साम्राज्यवाद का मार्ग अपनाने के लिए मजबूर कर देता है।"²

उपनिवेशवादी नीति और साम्राज्यवादी नीति के बीच बहुत थोड़ा अन्तर होता है। साम्राज्यवाद का अस्तित्व वहाँ ममझा जाता है जहाँ स्थानीय विरोध का अन्त करने के लिए, उपनिवेशवाद कायम रखने के लिए या अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जहाँ यह शक्ति प्रयुक्त नहीं की जाती तथा जहाँ विदेशी शासन के प्रति कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया जाता, वह उपनिवेशवाद कहलाता है। संयुक्तराज्य अमेरिका ने फिलीपाईंस को स्पेन मुक्त कराने के बाद उस पर औपनिवेशिक शासन लागू किया। उपनिवेशवाद और

1 J. A. Hobson : Imperialism-A Study, 1948, p. 7.

2 Buell, Raymond L. : International Relations, 1929, p. 315.

साम्राज्यवाद के बीच का अन्तर स्वानुभूतिपूर्ण है और अंशतः सम्बन्धित लोगों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। पैडलफोर्ड तथा लिबन के अनुसार दो प्रकार के प्रशासनों को सामान्य रूप से साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी शासन नहीं समझा जाता। प्रथम, उन संरक्षित देशों का प्रशासन जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के समझौते के अधीन हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनेक छोटे-छोटे पराधीन देशों को संरक्षण परिषद् के अधीन रख दिया गया जो बड़े देशों को पृथक् रूप से प्रारम्भ-प्रशासन की क्षमता का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंप देनी है। दूसरे, किसी अन्य राज्य के प्रदेश में अस्थायी हस्तक्षेप को भी उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी नहीं कहा जा सकता जो अल्पकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया हो, जैसे वहाँ रहने वाले अपनी राष्ट्रीयता के लोगों की सम्पत्ति एवं जीवन की रक्षा के लिए अथवा शान्ति कायम रखने के लिए। यहाँ हस्तक्षेप का उद्देश्य शासन स्थापित करना नहीं होना। संयुक्तराज्य अमेरिका ने सन् 1964 में वहाँ रहने वाले मिशनरियों की सहायता के लिए काँगो में हस्तक्षेप किया। सन् 1965 में अमेरिका ने अमेरिकी राज्यों के संगठन के सहयोग से गृहयुद्ध की स्थिति रोकने के लिए डोमिनिकन गणराज्यों को सेनाएँ भेजीं। जब एक राष्ट्र किसी देश के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो उसे साम्राज्यवादी कहा जा सकता है। जब ग्रेट ब्रिटेन की सेनाओं को सन् 1965 में जाम्बिया में रोडेिशिया सरकार द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों से देश की रक्षा के लिए आमन्त्रित किया गया तो ग्रेट ब्रिटेन को साम्राज्यवादी कहा गया। इन दोपारोपणों से बचने के लिए राज्य को अपने ऐसे कार्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। काँगो, साइप्रस, स्वेज-प्रदेश, आदि स्थानों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की अस्थायी शान्ति-सेनाएँ रखी गई हैं। उनको साम्राज्यवाद का प्रतीक नहीं माना जाता क्योंकि उनका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय है और वे जहाँ स्थित हैं वहाँ की स्थानीय सरकार का उनको समर्थन प्राप्त है। यह माना जाता है कि इन शान्ति-सेनाओं का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय समाज की ओर से शान्ति कायम रखना है, इसलिए यहाँ अपने ऐतिहासिक अर्थ में 'साम्राज्यवाद' शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

साम्राज्यवाद की नींव के पत्थर

(Foundation Stones of Imperialism)

साम्राज्यवाद का विशाल भवन क्यों निर्मित किया जाता है तथा उसके स्थिर रहने का क्या आधार है यह जानना साम्राज्य के समर्थकों एवं आलोचकों दोनों के लिए उपयोगी है। जिस प्रकार आधार को मजबूत करके साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को उकसाया जा सकता है उसी प्रकार आधार को कमजोर करके साम्राज्यवाद के महल को गिराया भी जा सकता है। साम्राज्यवाद के अधीनस्थ क्षेत्र, जिनको प्रायः सम्पत्ति (Possessions), उपनिवेश (Colonies), रक्षित-राज्य (Protectorates), अर्द्धरक्षित राज्य (Semi-protectorates) और आश्रित राज्य (Dependent States) आदि की संज्ञा दी जाती है, साधारणतया अपनी स्थिति से कभी सन्तुष्ट नहीं रहते। साम्राज्यवादी देश और प्रभावित राज्यों के आर्थिक,

सामाजिक, धार्मिक आदि हित परस्पर टकराते हैं और यही कारण है कि उनके बीच सघर्ष और कटु भाव बने रहते हैं। कारण यह है कि साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा प्रभावित प्रदेशों का प्रायः शोषण किया जाता है, उनका दमन किया जाता है तथा उनका इतना दमन किया जाता है कि वे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए तिलमिला उठते हैं। प्रभावित प्रदेशों के सतत् और कड़े विरोध के बाद भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपने पाँव जमाए रखती हैं। ऐसा क्यों होता है यह जानने के लिए यह ज्ञात करना उपयुक्त रहेगा कि साम्राज्यवाद के उद्देश्य अथवा कारण क्या हैं।

1 **डार्विन का सिद्धान्त (Darvin's Theory)**—डार्विन ने जीव विज्ञान में दो सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया। पहला था जीवन के लिए सघर्ष (Struggle for Existence) और दूसरा था योग्यतम का उत्तर जीवन (Survival of the Fittest)। ये सिद्धान्त सामाजिक जीवधारी रचना (Social Organism) पर लागू नहीं होते, फिर भी ये अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गए हैं। लैंगर (Langer) के मतानुसार इसने विस्तार के लिए एक दैवी अनुमोदन (Divine Sanction) प्रदान किया है।

साम्राज्यवाद मूल रूप से मनुष्य की लुटेरी प्रवृत्तियों का परिणाम है। जिस प्रकार छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है उसी प्रकार छोटे राष्ट्रों का बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा शक्ति तथा हिंसा द्वारा शोषण किया जाता है। राज्यों में शक्ति के लिए सघर्ष (Struggle for Power) बहुत पहले से ही पाया जाता है। प्रो. शुमन (Schuman) के विचार से आधुनिक साम्राज्यवाद शक्ति प्राप्त करने की इच्छा तथा विजय प्राप्त करने की लालसा की एक नई अभिव्यक्ति है। प्रायः सभी तानाशाह और सर्वाधिकारवादी राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में साम्राज्यवाद का समर्थन और अनुपालन करते हैं। जिस प्रकार साम्यवादी चीन जपान को भेड़ों के नीचे लाना चाहता है वैसे ही हिटलर भी सारे विश्व को जर्मनी के अधीन लाना चाहता था। मुसोलिनी ने शक्ति एवं साम्राज्य प्राप्ति की इच्छा को ही फासिस्ट राज्य बताया था। उसके मतानुसार साम्राज्यवाद का अर्थ प्रादेशिक, सैनिक और व्यापारिक विस्तार के साथ आध्यात्मिक और नैतिक प्रसार भी था। साम्राज्यवादी विस्तार को सर्वाधिकारवादी देश द्वारा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यही कारण है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों की जनता अपने तानाशाहों की नीतियों को पूर्ण समर्थन प्रदान करती है। इस कोहन (Hans Kohn) के मतानुसार साम्राज्यवाद में मनोवैज्ञानिक लक्ष्यों का बड़ा महत्त्व है। साम्राज्यवादी देश की जनता स्वयं राज्य से अधिक उच्च है तथा साम्राज्य को अपने सम्मान, गौरव एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक मानती है।¹

2 **बढ़ती हुई आबादी (Growing Population)**—यह तर्क दिया जाता है कि बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए नए साम्राज्य बनाना और नए उपनिवेश

1 William L. Langer : 'A Critique of Imperialism', Foreign Affairs, XIV (Oct. 1935), p. 109.

प्राप्त करना आवश्यक है। इटली, जापान आदि देशों ने समय-समय पर अपनी नीतियों के समर्थन में इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए थे। किन्तु यथार्थ में यह तर्क अधिक सार्थक नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि साम्राज्यवादी देशों की बहुत थोड़ी जनता उपनिवेशों में जाकर बसती है। जब तक जितने लोग उपनिवेशों में जाकर बसते हैं, तब तक देश में उतने नए लोग जन्म ले लेते हैं।

3 आर्थिक उपलब्धियाँ (Economic Achievements)—आर्थिक कारण प्रारम्भ से ही साम्राज्यवाद के सबसे अधिक मौलिक कारणों में से एक रहा है। साम्राज्यवादी देशों में प्रायः कच्चे माल की कमी पाई जाती है। वे इस कमी को अपने उपनिवेशों से पूरा करते हैं। डॉ. शाक्ट (Dr. Shacht) के अनुसार विश्व की राजनीति में होने वाले अधिकांश संघर्षों का आधार कच्चे माल की प्राप्ति होता है। साम्राज्यवादी राज्य प्रायः औद्योगिकृत (Industrialized) हैं। उत्पादित माल को खपाने के लिए उपनिवेशों में बाजार खोजे जाते हैं। इसी अर्थ में वेम्बरलेन कहा करता था कि साम्राज्यवाद का अर्थ है 'वारिज्य'। दूसरी ओर कुछ विचारकों के मतानुसार साम्राज्यवाद द्वारा वारिज्य को अधिक लाभ नहीं मिल पाता। ब्यूएल (Buell) के अनुमान से विश्व के व्यापार का पाँचवाँ भाग उन देशों के साथ होता है जो साम्राज्यवाद के अधीन हैं जबकि स्वतन्त्र देशों के साथ होने वाले व्यापार की मात्रा 4/5 भाग है। साम्राज्यवाद एक देश को ऐसे प्रवसर प्रदान करता है कि वह विदेशों में पूँजी लगा सके। अमेरिका ने विभिन्न देशों में पूँजी लगा रखी है, यही कारण है कि वह उन देशों की आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करता रहता है। यह डॉलर कूटनीति (Dollar Diplomacy) कहलाती है। कुछ विचारकों के अनुसार तो यह उतनी ही उपयोगी तथा प्रभावशाली होती है जितनी कि एक सशस्त्र सेना। प्रो. पामर तथा पकिस ने साम्राज्यवाद होने वाली इन समस्त आर्थिक उपलब्धियों का अच्छा विवेचन किया है।

साम्राज्यवाद का आर्थिक कारण पर्याप्त लोकप्रिय माना जाता है। साम्यवादी विचारकों ने, मुख्य रूप से लेनिन ने, साम्राज्यवाद को पूँजीवाद के अन्तर्विरोधों का ही परिणाम माना है। लेनिन की व्याख्या के अनुसार पूँजीवाद में एकाधिकार की प्रवृत्ति का विकास होता है और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था के कारण वह क्षपण के लिए बाजारों की माँग करता है। पूँजीवादी व्यवस्था की इस माँग के कारण ही साम्राज्यवाद के बल पर अनिश्चित भूमि प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। साम्राज्यवाद और आर्थिक तत्त्व के बीच इतना गहरा सम्बन्ध है कि साम्राज्यवाद के एक रूप को ही आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाता है। बारबरा वार्ड (Barbara Ward) के मतानुसार आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ होता है जिसमें एक बाहरी शक्ति स्थानीय साधन-स्रोतों को अपने अधिकार में कर लेती है और उन्हें मुख्य रूप से या पूरी तरह से अपने लाभ के लिए प्रयुक्त करती है। आजकल यह परिभाषा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि आज की आर्थिक स्थिति में

विभिन्न देश आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में अनेक नए राजनीतिक एवं नैतिक विरोधाभास उत्पन्न होते हैं।

विदेशी आर्थिक प्रभाव व्यक्तिगत पूँजी लगाने से हो सकता है और सरकारी आर्थिक कार्यों द्वारा भी। किन्तु इस नियन्त्रण की मात्रा और विधियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। कुछ बड़े औद्योगिक देश अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की पूँजी, बाजार और विनिमय व्यवस्था को मुख्यतः निजी उद्यमों के माध्यम से नियन्त्रित करते हैं। मध्यपूर्व से जो तेल का व्यापार किया जाता है वह बहुत कुछ व्यक्तिगत विदेशी निगमों के माध्यम से किया जाता है, यद्यपि इन क्रियाओं से स्थानीय राजनीतिक इकाइयाँ भी लाभान्वित होती हैं। आर्थिक कार्यों की सम्पन्नता के तरीके के आधार पर ही यह निश्चित किया जाता है कि इसे हम सहयोगी विकास के रूप में वर्गीकृत करें अथवा साम्राज्यवादी शोषण के रूप में। आधुनिक काल में सरकार द्वारा जो विदेशी सहायता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं उनको भी साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता है।

4. व्यक्तिगत उपलब्धियाँ (Personal Gains)—साम्राज्यवादी कार्यक्रमों द्वारा बहुत से लोगों का पोषण होता है। इससे साम्राज्यवादी देश के व्यापारियों को लाभ होता है क्योंकि उनको उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा और स्रोत दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। उनको पर्याप्त रूप से कच्चा माल मिल जाता है तथा निर्मित माल की खपत के लिए बाजार भी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार साम्राज्यवाद के साथ देश के व्यापारियों के हित जुड़ जाते हैं और यही कारण है कि वे इन नीतियों को पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ विदेशी उप-वाणिज्य दूतों (Pro-consuls), कूटनीतिज्ञों (Diplomats) तथा विदेशी अतिरिक्त प्रशासन-अधिकारियों (Civil-Servants) के अनेक स्थान रिक्त होने हैं। फलतः साम्राज्यवादी देश के अनेक नागरिकों को इससे रोजगार प्राप्त होता है। इन सबके अतिरिक्त साम्राज्यवादी देश की सेना के एक बहुत बड़े भाग का विदेशी खर्च पर पोषण होता है। कहा जाता है कि सन् 1945 से पूर्व प्रत्येक चार अंग्रेजों में से एक की जीविका का भार भारत पर पड़ता था। साम्राज्य के कारण जिन लोगों का स्वार्थ पूरा होता है वे अपेक्षाकृत देश के स्वशासित होने के प्रत्येक उपाय का दृढ़ता से विरोध करते हैं। साम्राज्यवाद में निहित स्वार्थ रखने वालों का एक वर्ग बन जाता है जिसका सदैव यही प्रयास रहता है कि साम्राज्य का विस्तार और सुरक्षा हो।

5 राष्ट्रीय सुरक्षा (Defence of the Nation)—सुरक्षा की दृष्टि से प्रायः शान्तिप्रिय देश भी साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाने लगते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक बड़ा विरोधाभास है कि यदि कोई देश शान्ति का समर्थक एवं इच्छुक है तो उसे बड़े से बड़े युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि कमजोर देश शक्तिशाली देशों के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में निष्कर्ष यह है कि यदि आप किसी अन्य राष्ट्र का साम्राज्य बनने से बचना चाहते हैं और अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं तो

साम्राज्यवाद के पक्ष पर आगे बढ़िये । अपने देश की सीमाओं को शत्रु से संरक्षित रखने के लिए सीमा के निकटवर्ती इलाकों को रक्षित-राज्य, अर्द्धरक्षित राज्य, प्रभावकारी क्षेत्र प्रथवा मध्यवर्ती राज्य (Buffer State) बना देना उपयोगी रहता है । उन्नीसवीं शताब्दी में रूस से भारत की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान, फारस और तिब्बत आदि राज्य से मध्यवर्ती राज्य (Buffer State) का काम लिया था । अधिकृत राज्यों के कच्चे माल और मनुष्य-शक्ति (Man-power) का प्रयोग कर साम्राज्यवादी देश अपनी अर्थ-व्यवस्था को भी मजबूत बना सकता है ।

6. साम्राज्यवाद का धार्मिक आधार (Religion as the basis of Imperialism)—धर्म-प्रचारकों और साम्राज्यवादियों के हित प्रायः एक स्थल पर जाकर मिल जाते हैं । जहाँ धर्म-प्रचारक यह चाहता है कि उसकी वापसाओं को दूर करने के लिए राज्य-शक्ति उसका समर्थन करे, वहाँ साम्राज्यवाद यह सोचता है कि उसकी नीतियों की वंशरता को ढकने के लिए और नीतियों को एक आदर्शवादी रूप प्रदान करने के लिए धर्म प्रचारकों का सहयोग मिल जाए । फलतः दोनों का स्वार्थपूर्वक गठबन्धन हो जाता है और सेनाएँ 'जिहाद' या 'धर्म युद्ध' का नाम लेकर साम्राज्यवादियों की महत्वाकांक्षाओं को तृप्त करने के लिए आगे बढ़ती चली जाती हैं । इतिहास में ऐसे गठबन्धनों द्वारा साम्राज्य-निर्माण के उदाहरणों की कमी नहीं है । सत्रहवीं शताब्दी में 'स्पाम' पर फ्रांस का अधिकार जेसुइट (Jesuit) धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया था । अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार में लन्दन की धर्म-प्रचार-समिति (Missionary Society) ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था । अमेरिकी राष्ट्रपति काल्विन कूलिज (Calvin Coolidge) का कहना था कि अमेरिका द्वारा जो सेनाएँ विदेशों में भेजी जाती हैं उनके साथ तलवार में होकर 'क्रास' (+) होता है ।

धर्म-प्रचार का प्रभाव साम्राज्यवाद के निर्माण में तो अनुकूल रहता है, किन्तु जब उसकी रक्षा का प्रश्न आता है तो धर्म-प्रचार अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी बन्धनों को ढीला करता है । भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारणों में धर्म-गुधार आन्दोलनों का बड़ा महत्त्व है । ईसाईयों मिशनरियों द्वारा भारतीयों को सुशिक्षित, जागरूक, स्वतन्त्रता-प्रेमी एवं मानवतावादी बनाकर अनजाने ही साम्राज्यवादियों का विरोध करने के योग्य बना दिया गया था ।

7. मानवतावादी दृष्टिकोण (Humanistic Outlook)—साम्राज्यवादी नीतियों के समर्थक मानवतावादी तर्कों के आधार पर अपने पक्ष का प्रोत्पन्न करते हैं । यह कहा जाता है कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ पिछड़े हुए देशों में व्याप्त अज्ञान, अशिक्षित शासन, न्याय सम्बन्धी आदिम विचार आदि बुराइयों को दूर करके वहाँ ज्ञान, विवक्षित शासन तथा आधुनिक विचारों की स्थापना करती हैं । असम्पन्न देशों में जहाँ दासता, मनुष्य भक्षण, कर्जदारी, मृदलोरी आदि की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, वहाँ साम्राज्यवादी देशों द्वारा सभ्यता का दीप जलाया जाता है । साम्राज्यवाद के समर्थक सीनेटर बेवरिज (Beveridge) का कहना था कि ईश्वर ने हमें (अमेरिकियों

को) प्रशासकीय दक्षता प्रदान की है और हमारा यह कर्त्तव्य है कि जंगलियों तथा असभ्यों पर शासन करें। सन् 1893 ई. में डिजरेली (Disraeli) ने घोषणा की थी कि यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम अफ्रीका को सम्य बनाने के कार्य में हाथ बटाएं। साम्राज्यवादी देशों के अधिकांश विचारक साम्राज्यवाद को मानवता की कसौटी पर वांछनीय ठहराते हैं किन्तु अधिकृत राज्यों अथवा साम्राज्यवादी शक्तियों से शासित राज्यों के विचारक इस दृष्टिकोण के समर्थक नहीं हैं। अपवादस्वरूप कुछ विचारकों को छोड़कर अधिकांश तो साम्राज्यवाद के काले कारनामों का ही चित्रण करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवतावादी तर्कों द्वारा साम्राज्यवाद को न्यायोचित ठहराना तथा इसे काले लोगों को सम्यता सिखाने के गोरे लोगों के उत्तरदायित्व (The White Man's Burden) की पूर्ति बताना एकपक्षीय, भ्रामक एवं मिथ्या तर्कों पर आधारित है।

साम्राज्यवाद के रूप (Forms of Imperialism)

साम्राज्यवाद को चाहे पामर तथा पकिंस द्वारा परिभाषित अर्थ में लिया जाए अथवा मॉर्गन्थो द्वारा परिभाषित अर्थ में, हम देखते हैं कि मात्रा और गुण के अनुसार इसके कई रूप हो सकते हैं। यदि 'साम्राज्यवाद' उच्च और निम्न (Superior and Inferior) के बीच शक्ति-सम्बन्धों (Power Relations) का नाम है तो हमें यह भी देखना होगा कि (Superiority) किन-किन विषयों में उच्चता है और किन-किन में नहीं है तथा सर्वोच्चता का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इस दृष्टि से साम्राज्यवाद के निम्न रूप हो सकते हैं—

1. संरक्षित तथा अर्द्ध-संरक्षित राज्य (Protectorate and Semi-protectorate)
2. प्रभाव के क्षेत्र (Spheres of Influence)
3. बाह्य प्रादेशिकता (Extra-territoriality)
4. अनौपचारिक नियन्त्रण (Informal Control)
5. शुल्क का नियन्त्रण (Tariff Control)
6. संयुक्त विदेशी प्रशासन (Condominium)
7. आर्थिक नियन्त्रण (Financial Control)
8. पट्टा (Lease-hold)

साम्राज्य-निर्माण में जो साधन अपनाए जाते हैं उनके अनुसार मॉर्गन्थो ने साम्राज्यवाद के तीन रूपों का वर्णन किया है। उनके मतानुसार साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीन साधनों को अपनाया जा सकता है। ये साम्राज्यवाद के साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य भी तीन प्रकार के हो सकते हैं—

1. राजनीतिक रूप से संगठित सारी पृथ्वी पर शासन करना।
2. केवल महाद्वीपीय प्रदेशों पर शासन करना।
3. स्थानीय प्रदेशों पर शासन करना।

इन साध्यों को प्राप्त करने के लिए जो सैनिक, आर्थिक एवं मौलिक साधन प्रयोज्य होते हैं उनको प्रायः साध्य समझने की भूल कर दी जाती है। साधनों के अनुसार साम्राज्यवाद का रूप भी बदल जाता है। सैनिक साम्राज्यवाद में सैनिक विजय (Military Conquest) की जाती है, आर्थिक साम्राज्यवाद में दूसरे लोगों का आर्थिक शोषण किया जाता है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में एक संस्कृति के स्थान पर दूसरी संस्कृति की प्रस्थापना की जाती है। इन तीनों ही रूपों के अधीन जो भी नीतियाँ अपनाई जाती हैं उनका लक्ष्य साम्राज्यवादी अर्थात् वस्तु-स्थिति (Status-quo) को बदलना होता है।

साम्राज्यवाद का सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्राचीन रूप सैनिक विजय है। आज तक जितने भी विजेता हुए हैं, वे प्रायः सभी बड़े-बड़े साम्राज्यवादी थे। सैनिक साधनों से जब साम्राज्य-निर्माण का कार्य किया जाता है तो पराजित राज्यों को इसकी प्रक्रिया बड़ी शीघ्रता से होती है और वे भी उन्हीं साधनों एवं नीतियों को अपनाते हैं जो साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा अपनाई थी। इस प्रकार 'साम्राज्यवाद' साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देता है। साम्राज्यवाद का दूसरा रूप 'डॉलर साम्राज्यवाद' कहलाता है। यह धातुनिक युग की उपज है तथा सैनिक साम्राज्यवाद की तुलना में कम विध्वंसात्मक तथा कम प्रभावशाली है। इन दोनों से भिन्न सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक सूक्ष्म साधन है। यदि कोई देश इसका सफल प्रयोग कर सकता है तो यह माना जाएगा कि उसकी साम्राज्यवादी कुशलता तीक्ष्ण है। मॉर्गन्थो कहते हैं कि साम्राज्यवाद के इस रूप का उद्देश्य न तो प्रदेश जीतना होता है और न उसके आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण करना; इसका लक्ष्य तो व्यक्तियों के मस्तिष्कों को जीतना व उस पर नियन्त्रण करना होता है ताकि दो देशों के बीच के शक्ति-सम्बन्धों को बदला जा सके। आजकल सांस्कृतिक साधन को साम्राज्यवाद के अन्य साधनों के सहायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा शत्रु को नष्ट बना कर सैनिक आक्रमण घटवा आर्थिक शोषण के लिए भूमि तैयार की जाती है।

साम्राज्यवाद का मूल्यांकन : दोष एवं प्रतिरोध

(Imperialism-An Evaluation)

दोष —अमेरीकी साम्राज्यवाद के बारे में प्रायः यह कहा जाता था कि अमेरीकी साम्राज्य विश्व-व्यापी न्याय और उदारता का चिरन्तन स्रोत (Perennial Spring) है जिस पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता। कोह्न (Kohn) का विचार है कि एशिया और अफ्रीका में जातीय एवं आर्थिक शोषण, गरीबी और युद्धों की रचना करने वाला साम्राज्यवाद नहीं था क्योंकि ये सारी बातें वहाँ पहले से ही वर्तमान थी। एशिया के लोग एशिया के दूसरे निवासियों को दास बनाते थे तथा अफ्रीकी जातियाँ दूसरी अफ्रीकी जातियों को अपना दास बना लेती थी। कोह्न के अनुसार पश्चिमी साम्राज्यवाद में अन्य दोष हो सकते हैं, किन्तु यह तो सच है कि इन प्रदेशों में उन्होंने जाति फँसाई और सन्मत्ता का पाठ पढ़ाया। पाप और पश्चिम के मतानुसार साम्राज्यवाद के समर्थकों द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें बहुत कुछ सत्य है।

साम्राज्यवाद के लाभ और हानियों का लेखा-जोखा करने के बाद अधिकांश विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह एक बुराई है। इससे प्राप्त होने वाले जिन लाभों की आशा की जाती है वे काल्पनिक अधिक हैं। यदि वे प्राप्त भी होते हैं तो इस रूप में प्राप्त होते हैं कि उनका महत्त्व ही समाप्त हो जाता है। साम्राज्यवाद का इतिहास हिंसा, युद्ध, दमन, शोषण, असमानता और दबर्तापूर्ण कारनामों से भरा हुआ है। साम्राज्यवाद विश्व-शान्ति के लिए राहु के समान है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व बार्नेस (Barnes) ने लिखा था कि "ब्रिटेन इतने बड़े साम्राज्य का भकेला ही स्वामी था, यह बात विश्व-शान्ति से मेल नहीं खाती, क्योंकि सत्तार के अन्य पूँजीवादी देशों की यह शिकायत रहनी थी कि इसके कारण उनको सत्तार के व्यापार और भू-प्रदेशों में उचित भाग नहीं मिल पाता।" ऐसे असन्तुष्ट वातावरण में विश्व-शान्ति 'कच्चे धागो पर भूलती है।'

साम्राज्यवाद अमानवीय है। साम्राज्यवाद के समर्थन में ये तर्क दिए जाते हैं कि "यह मनुष्यों को इसलिए गुनाम बनाता है ताकि वे स्वतन्त्रता का महत्त्व सीख सकें, वह उनका इसलिए दमन करता है ताकि उनमें स्वशासन के लिए प्रेम उत्पन्न हो सके, उनका इसलिए आर्थिक शोषण किया जाता है ताकि वे गरीब बनने के बाद उद्योगों में बरबस पहुँच करना सीखें; तथा साम्राज्यवाद में अधिकृत प्रदेशों की जानियों को इसलिए हीन और तुच्छ समझा जाता है जिससे कि उनमें आत्म-सम्मान तथा परस्पर एकता की भावनाएँ जाग्रत हो सकें।" ये सभी तर्क बड़े हान्योत्पन्न हैं तथा प्रायः उद्देश्य और परिणाम में भ्रम पैदा करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यह हो सकता है कि साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में ये सब परिणाम निकलें किन्तु साम्राज्यवाद इन परिणामों को अपना लक्ष्य बनाकर कभी नहीं चलता। व्यवहार में हम देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आन्दोलनों को साम्राज्यवादी सरकार द्वारा किस प्रकार दबाया गया था, भारतीयों को राजनीतिक अधिकार एवं स्वतन्त्रता कितने त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त हुए थे। अब यह वह बर विश्व को भुलावे में नहीं रखा जा सकता कि इन सब नीतियों के पीछे (फूट डालो और राज्य करो के व्यवहार के पीछे) भारतवासियों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। कोई यह स्वीकार नहीं कर सकता कि जनरल टायर ने भारतीयों को मशीनगनों से इसलिए भूना था कि उनका दूसरा जन्म किसी स्वतन्त्र और समृद्ध देश में हो। पार्कर मून (Parker Thompson Moon) के मतानुसार अंग्रेज पहले-पहल भारत में आए और आकर बस गए। इसका कारण यह नहीं है कि वे भारत की भलाई चाहते थे बल्कि यह था कि वे ब्रिटेन की भलाई चाहते थे। महात्मा गाँधी कहा करते थे कि भारत में अंग्रेजी कानून के शासन (Rule of Law) का लक्ष्य जनता का शोषण था।

साम्राज्यवाद वैयक्तिक स्वतन्त्रता का विरोधी है। राजनीतिक दासता को साम्राज्यवाद का अभिन्न अंग माना जाता है। साम्राज्यवादी शक्तियों की निरन्तर पराधीनता में रहने वाले लोग स्वतन्त्रता की अपना जन्म-सिद्ध अधिकार बहूना दिनों

वाद समझ पाते हैं। लोग पालतू कुत्तों को प्रायः इसलिए भाँस नहीं देते कि कहीं किसी दिन भूल से घ्रपने स्वामी को काट लें। यही मनोवृत्ति एक साम्राज्यवादी शासन की होती है। अपनी औपनिवेशिक जनता का शोषण करने वाली साम्राज्यवादी सरकार उसे वास्तविक स्वतन्त्रता देना चाहेगी, यह आशा नहीं की जा सकती। भ्रत्याचार, दमन और परतन्त्रता की चक्री में पिसती हुई जनता जब भ्रान्तिकारी बन जाती है, स्वाधीनता के लिए तडपने लगती है और साम्राज्यवादी शक्ति ममझ जाती है कि उस जनता को अब अधिक समय तक गुलाम बनाए नहीं रखा जा सकता, तभी वह उसे स्वतन्त्रता देने को विवश होती है। भारत का स्वाधीनता आन्दोलन इस बात का जीता-जागता ज्वलन्त प्रमाण है।

प्रतिरोधात्मक उपाय और कठिनाइयाँ—साम्राज्यवाद के दोषों के सदम में यह विचार किया जाने लगा है कि साम्राज्यवाद का विरोध किस प्रकार किया जाए। कुछ विचारकों ने साम्राज्यवाद को समाप्त करने के बजाए उसे सशोधित करने के उपाय सुझाए हैं। पार्कर मून (Parker Moon) का कहना है कि साम्राज्यवाद मध्य-विक्टोरियन युग का बचा खुचा भंश है जो एक नितान्त गैर-विक्टोरियन युग में कायम है। यदि संक्रमणकाल में साम्राज्यवाद अपना औचित्य सिद्ध करना चाहता है तो उसे शोषण-मूलक न होकर उत्तरदायित्व-मूलक होना चाहिए। कुछ विचारकों के मतानुसार साम्राज्यवाद को बदलने, सशोधित करने या अन्त करने से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की भावना का प्रचार करके लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। दूसरे लोग साम्राज्यवाद को सशोधित करने के लिए निम्न सुझाव देते हैं—

1. गोरी जाति को उच्चता प्रदान न की जाए,
2. साम्राज्यवादी देश मजदूरों का शोषण न करे;
3. पिछड़े देशों में व्यक्तिगत पूँजी के प्रयोग को नियन्त्रित रखा जाए;
4. पिछड़े देशों को स्वशासन के योग्य बनाया जाए;
5. बार्नेस (Barnes) के मतानुसार साम्राज्यवाद की जड़ें हिलाने के लिए उसके मुख्य आधार पूँजीवाद पर चोट की जाए। यह अन्ध्रा रहेगा कि मातृदेश ने पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना की जाए।

पूँजीवाद का विरोध करने के लिए मॉर्गेंथो ने उन नीतियों का वर्णन किया है जो विभिन्न देशों द्वारा समय-समय पर अपनाई जानी रही है। ये नीतियाँ मुख्य रूप से तीन हैं—

1. तुष्टिकरण की नीति (Policy of Appeasement)
2. घेराबन्दी नीति (Policy of Containment)
3. भय की नीति (Policy of Fear)

मॉर्गेंथो का कहना है कि साम्राज्यवाद की प्रतिनिध्या के रूप में जब कोई राष्ट्र तुष्टिकरण या भय की नीति अपनाता है तो उसके कार्यों का परिणाम प्रायः

साम्राज्यवाद को सङ्गठित व अधिक शक्तिशाली बनाने के रूप में होता है। साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करने के मार्ग में कई कठिनाइयाँ हैं—

प्रथम, विजय की नीति को तभी साम्राज्यवादी माना जा सकता है जबकि वह यथा-स्थिति (Status-quo) को बदलने का प्रयास करे, किन्तु यह अन्तर बड़ा बठिन है कि कौन-सी नीति वास्तव में साम्राज्यवाद की परिधि में आती है और कौन-सी नहीं।

दूसरे, जब एक देश यथा-स्थिति कायम रखने की नीति अपनाता है तो यह निश्चित नहीं रहता कि वह अपनी इस नीति को छोड़कर कब साम्राज्यवादी बन जाएगा।

तीसरी, जब तक एक देश स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाता है तो उसकी अन्य नीतियों के उद्देश्यों को भी क्षेत्र (Territory) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है अर्थात् यह कहा जा सकता है कि यह देश अमुक प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। किन्तु परेशानी तो एक देश द्वारा अपनाई गई सांस्कृतिक तथा आर्थिक नीतियों का उद्देश्य स्पष्ट करते समय होती है। यह जानना बहुत मुश्किल है कि एक देश द्वारा अपनाई जाने वाली सांस्कृतिक एवं आर्थिक नीति का उद्देश्य साम्राज्यवादी है अथवा नहीं। स्विट्जरलैंड द्वारा विश्व के प्रदेशों में सक्रिय आर्थिक नीतियाँ अपनाई जाती हैं, किन्तु उनको साम्राज्यवादी नीति नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार स्पेन का लेटिन अमेरिका की संस्कृति में प्रवेश साम्राज्यवाद की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि अमेरिका की तुलना में स्पेन की गैरिक शक्ति इतनी नहीं कि स्पेन द्वारा शक्ति-सम्बन्धों को अपने पक्ष में परिवर्तित करने का कोई प्रयास किया जा सके।

चौथे, इन समस्त परेशानियों के बावजूद भी यदि यह प्रमाणित हो जाए कि एक देश की नीति साम्राज्यवादी है, तो यह कठिनाई प्रा उपस्थित होती है कि इस बात का निश्चय कैसे किया जाएगा कि साम्राज्यवाद का लक्ष्य क्या है अर्थात् यह देश केवल क्षेत्रीय आधिपत्य चाहता है या महाद्वीपीय अथवा सम्पूर्ण पृथ्वी पर ही शासन करना चाहता है? सफलताओं और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ प्रायः साम्राज्यवाद का लक्ष्य भी परिवर्तित होता रहता है। सम्पूर्ण पृथ्वी पर शासन करने का लक्ष्य लेकर चलने वाला देश जब प्रारम्भिक प्रयासों में सफल नहीं हो पाता तो उसे अपना लक्ष्य बदलना पड़ता है। उसी प्रकार एक राज्य, जो केवल स्थानीय प्रदेशों पर ही अधिकार करने का लक्ष्य लेकर चलता है और इस लक्ष्य में सफल हो जाता है तो वह महाद्वीप-विजय का और बाद में सारी पृथ्वी पर शासन करने का उद्देश्य भी बना सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि साम्राज्यवाद में एक गतिशील ताकत (Dynamic Force) है। इस प्रकार साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ तथा उनकी प्रतिक्रियावादी नीतियाँ कभी निश्चय नहीं होनी; दोनों ही बदलती रहती हैं तथा इनका मूल्यविन भी समय-समय पर होना रहता है।

पाँचवीं और अन्तिम कठिनाई यह है कि साम्राज्यवाद अपने आपको इस प्रकार प्रवर्धित करता है कि इसके सही रूप को नहीं समझा जा सकता। एक देश की विदेश-नीति अथवा साम्राज्यवादी नीति जैसी दिखायी देती है और जैसी वह वास्तव में होती है—इन दोनों के बीच भारी अन्तर रहता है। आज सर्वांगीण युद्ध के युग में यह आवश्यक हो गया है कि साम्राज्यवाद के प्रसार को रोका जाए, उसका रूप परिवर्तित किया जाए और हो सके तो उसे समाप्त किया जाए। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य शान्ति-दूत साम्राज्यवाद की विध्वंसकता को घटाने व इसके प्रसार को कम करने में प्रयत्नशील हैं, किन्तु उनको कितनी सफलता प्राप्त हो सकेगी इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा।

उपनिवेशवाद एवं नव-उपनिवेशवाद (Colonialism and Neo-Colonialism)

साम्राज्यवाद के सन्दर्भ में हम प्रासंगिक रूप से उपनिवेशवाद पर कुछ चर्चा कर चुके हैं और बता चुके हैं कि दोनों के बीच का अन्तर इतना कम है कि प्रायः एक के लिए दूसरे का प्रयोग कर दिया जाता है। दोनों ही के तत्त्वों में काफी कुछ समानताएँ पायी जाती हैं तथापि दोनों में थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य है। साथ ही यह भी है कि पुराने उपनिवेशवाद के दिन लड़ चुके हैं और नए परिवेश में उपनिवेशवाद नए ढंग से अपने प्रसार के लिए प्रयत्नशील है जिसे आधुनिक अथवा नव-उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है।

उपनिवेशवाद (Colonialism)

उपनिवेशवाद आधुनिक साम्राज्यवाद का विकृत रूप है जिसका इतिहास कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज से प्रारम्भ होता है। पन्द्रहवीं एवं सोलहवीं शताब्दी में यूरोप के शक्तिशाली, सम्पन्न और विकसित देशों ने नए क्षेत्रों की खोज करके वहाँ अपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ कर दिए। साम्राज्यवादी शक्तियों ने प्रारम्भ में तो उपनिवेशों पर अपना राजनीतिक प्राधिपत्य स्थापित किया और तब वे उनका आर्थिक शोषण करने लगे। साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद की इस दोड़ में ब्रिटेन और फ्रांस काफी आगे निकल गए। जब उपनिवेशवासियों ने आर्थिक लूट का विरोध किया तो साम्राज्यवादी देशों के निवासियों ने उपनिवेशों में बसना शुरू कर दिया। उनके इस प्रकार बस जाने को 'उपनिवेशीकरण' (Colonization) की संज्ञा दी गई। उपनिवेशवाद और उपनिवेशीकरण में अन्तर को स्पष्ट करते हुए फ्रेंच विद्वान् रेमण्ड आरो (Raymond Aron) ने लिखा है, "उपनिवेशीकरण का अभिप्राय एक राष्ट्र तथा दो जातियों से है जैसे दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया आदि में हुआ जबकि उपनिवेशवाद से तात्पर्य दो राष्ट्र एवं दो जातियों से है। उपनिवेशवाद में भासक देश के अल्पसंख्यक साम्राज्यवादी सत्ता के प्रतिनिधि रूप में उपनिवेशों का प्रशासन चलाते हैं।"

उपनिवेशवाद को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। विन्सलो (Winslow) के शब्दों में, "यह अनाधिकृत भूमि पर आधिपत्य है जिसमें संघर्ष आकस्मिक रहा हो अथवा अनावश्यक हो तथा जो यूरोपवासियों की अपने रहने के लिए नई भूमि की खोज की आकांक्षा से अनुप्राणित हो।" वेबस्टर शब्दकोश (Webster Dictionary) के अनुसार, "उपनिवेशवाद उन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक नीतियों का नाम है जिन पर चलकर कोई साम्राज्यवादी शक्ति दूसरे देशों अथवा लोगों तक अपना नियन्त्रण बनाए रखना अथवा उसका विस्तार करना चाहती है।" इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपनिवेशवादियों का राजनीतिक लक्ष्य होता है—दूसरे लोगों के मन, व्यवहार, धर्म तथा साधनों पर राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित करना, सामाजिक नीति का लक्ष्य होता है—शैक्षिक योजनाएँ चलाकर धर्म प्रचार को सहायता पहुँचाना तथा दूसरे लोगों के मस्तिष्क में अपने विचार ठूसना, आर्थिक नीति का लक्ष्य होता है—दूसरे देशों तथा वहाँ के निवासियों का आर्थिक शोषण करना। शोषणकारी आर्थिक नीति उपनिवेशवाद का सबसे मुख्य अंग है। उपनिवेशवाद की दो प्रमुख विशेषताएँ होती हैं, प्रथम, अधीनस्थ लोगों को आत्म निर्णय के अधिकार से वंचित रखना, एवं द्वितीय, अधीनस्थ देश और उसके निवासियों का अधिकाधिक आर्थिक शोषण करना। ब्रिटेन ने भारत के साथ यही किया था। प्रारम्भ में अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए, धीरे-धीरे वे वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और फिर वहाँ के शासक बन बैठे और उन्होंने देश का खुलकर शोषण किया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका उपनिवेशवाद के केन्द्र बन गए। पुरातन उपनिवेशवाद का जो स्वरूप रहा है और नए चोले में वह पुनः किस प्रकार सक्रिय है—इसका विस्तार से स्पष्टीकरण आगे नव-उपनिवेशवाद के सन्दर्भ में किया जाएगा।

नव-उपनिवेशवाद

(Neo-Colonialism)

प्रख्यात रूसी विद्वानों जुकोव, देल्यूसिन, इस्तेदेरोव तथा स्तेपानोव ने आधुनिक अथवा नव-उपनिवेशवाद पर विस्तार से चर्चा करते हुए पारचात्य राष्ट्रों को और संयुक्त राज्य अमेरिका को नव-उपनिवेशवाद के प्रसार के लिए दोषी ठहराया है। उन्होंने उपनिवेशवाद के प्रसार में संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमिका की चर्चा की है। हम यहाँ उनके लेख के मारांश को प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे हमें उपनिवेशवाद के पुरातन स्वरूप और आधुनिक स्वरूप का भली-भाँति ज्ञान हो जाएगा। तथापि हम यह अवश्य कहना चाहेंगे कि नव-उपनिवेशवाद के प्रसार में लगभग सभी महाशक्तियों तथा महानतम शक्तियों का हिस्सा न तभी रूप में हाथ है। लेख का सारांश इस प्रकार है—

"एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के युद्धोत्तरकालीन विराम में मन्त्रन्ध्र साहित्य में कभी-कभी 'उपनिवेशित प्रणाली' और 'उपनिवेशवाद' के बीच अन्तर न बरने वाली तथा इन दोनों धारणाओं को समान मानने की प्रवृत्ति

पाई जाती है। चूंकि औपनिवेशिक प्रणाली समाप्त हो गई है, इसलिए निष्कर्ष निकाला जाता है कि उपनिवेशवाद भी खत्म हो गया है। किन्तु वास्तव में औपनिवेशिक प्रणाली का ध्वस्त होना किसी भी अर्थ में उपनिवेशवाद के अन्त का द्योतक नहीं है। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के राष्ट्र नित्य ही यह अनुभव करते हैं कि राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने और औपनिवेशिक शासन-व्यवस्था समाप्त हो जाने पर भी वे विदेशी शोषण प्रणाली अपने आन्तरिक मामलों में प्रभुत्व और बहुधा बहुत ही घृष्ट हस्तक्षेप से बच नहीं पाए हैं। शोषण और हस्तक्षेप की यह नीति ही आधुनिक उपनिवेशवाद अथवा नव-उपनिवेशवाद का स्वरूप है और इसे ऐसे तरीकों से घमेल में लाया जाता है, जिन्हें साम्राज्यवादियों ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बना लिया है।

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के राष्ट्रों के लिए उपनिवेशवाद, अर्थात् दूसरे देशों तथा राष्ट्रों को अपने अधीन करने तथा उनका शोषण करने की नीति सबसे अधिक घातक रही है और आज भी है।

जब वे देश औपनिवेशिक प्रणाली के दृढ़ पाश में बंधे थे, उस समय की अपेक्षा अब उपनिवेशवाद के ध्येय और तरीके बहुत ही अधिक जटिल हो गए हैं। आजकल कोई भी साम्राज्यवादी राष्ट्र किसी दूसरे देश पर न तो अपना प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सकता है और न बिना किसी स्पष्ट मुद्दावज के खुलेआम उसकी भौतिक सम्पदा को लूट सकता है। आधुनिक उपनिवेशवाद दूसरे देशों के राजनीतिक आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन पर अप्रत्यक्ष नियन्त्रण से ही मन्तुष्ट रहने पर विवश है। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के देशों में इस समय जो आमूल सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, वह उनके विकास को अपने स्वार्थ की दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है। फलतः नव-उपनिवेशवाद परम्परागत उपनिवेशवाद से दृढ़ दृष्टि से भिन्न है कि इसके रूप तथा तरीके बहुविध और इसके प्रभाव बहुत जटिल हैं।

फिर भी पुराने और नये उपनिवेशवाद की प्रकृति समान है। यही कारण है कि व्यवहार में नव-उपनिवेशवादी अपने ऐतिहासिक पूर्ववर्तियों के हथकण्डों का भी उपयोग खुलकर करते रहे हैं। सचीली तिकड़मबाजी और दलीलो के इस्तेमाल के साथ-साथ, जो नव-उपनिवेशवाद की विशेषता है, एशियाई, अफ्रीकी और लेटिन अमेरिकी देशों के राष्ट्रीय हितों तथा उनकी प्रभुसत्ता पर ऐसे सीधे और घृष्ट प्रहार किए जाते हैं कि औपनिवेशिक विजयों के गुम के सबसे शर्मनाक काण्डों की याद ताजा हो जाती है।

यदि युद्धोत्तर काल में पुराने औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे हैं तो इसका यह अन्निशय नहीं है कि साम्राज्यवादी एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में पुराने साम्राज्यों के ध्वंसावशेषों पर अथवा उनके निकटवर्ती इलाकों में अपने नये अधिकार तथा प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं। समुक्त राज्य

अमेरिका इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सक्रिय है, फलतः अनेक देश एक प्रकार से आज के अमेरिकी उपनिवेशवादियों द्वारा अधिकृत भू-भाग हो गए हैं।

इसके कुछ उदाहरण ये हैं—हिन्दचीन की जनता के शौर्यपूर्ण राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के फलस्वरूप दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस अंचल में फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रभुत्व समाप्त हुआ। चीनी जनक्रान्ति के फलस्वरूप अपदस्य च्यांग-काई-शेक के गुट के ताईवान भाग जाने का लाभ उठाकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने उस पर अर्थात् उस द्वीप पर कब्जा कर लिया, हालांकि यह चीन का अविच्छिन्न भाग है। च्यांग-काई-शेक गुट की सुरक्षा तथा सुख-सुविधा को अपनी जिम्मेदारी बनाकर संयुक्तराज्य अमेरिका ने ताईवान को न केवल एक सैनिक शिविर तथा चीनी प्रतिक्रान्ति के झड़्डे, बल्कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की एक प्रकार की अग्रिम चौकी में भी परिवर्तित कर दिया है।

किन्तु आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को फिर भी ध्यान में रखना पड़ता है और इसी कारण साम्राज्यवादी विजित देशों में स्वदेशी सरकारों को रखने के लिए विवश है। भण्डा बही बना रहता है, परन्तु पराधीन देशों के लिए आधुनिक साम्राज्यवादी जुए का भार तनिक भी हल्का नहीं होता।

उपर्युक्त तथ्य हमें इस बारे में विचार करने को मजबूर करते हैं कि क्या वर्तमान युग में पुराने, कानूनी दृष्टि से स्पष्ट गठित औपनिवेशिक साम्राज्यों का स्थान नए 'अदृश्य' साम्राज्य तो नहीं लेने लगे? दूसरे शब्दों में क्या औपनिवेशिक शासन-व्यवस्था का उन्मूलन एक प्रकार के औपनिवेशिक प्रभुत्व की जगह दूसरे प्रकार के औपनिवेशिक प्रभुत्व को कायम करना ही तो नहीं है।

यदि हम इस प्रश्न का ठीक उत्तर पाना चाहते हैं, तो हमें उन ऐतिहासिक शक्तियों को ध्यान में रखना होगा, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वर्तमान स्थिति का निर्धारण करती हैं। जिस काल में इन तीन महाद्वीपों में साम्राज्यवाद का एकछत्र आधिपत्य कायम था तब किसी एक उपनिवेश-स्वामी देश का अधिकार या प्रभाव सतम हो जाने का अर्थ केवल यह होना था कि उसकी जगह किसी अन्य साम्राज्यवादी लुटेरे ने ले ली है। मिमाल के लिए, प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ठीक यही हुआ, जब विजयी साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के उपनिवेशों को हथिया लिया था। इसी प्रकार औपनिवेशिक साम्राज्यों के दौर में अमेरिका ने विभिन्न उपनिवेशों तथा पराधीन देशों में अपनी स्थिति बहुत ही प्रभावकारी बना ली, जिसके फलस्वरूप अमेरिकी भण्डा फहराए बिना ही अमेरिकी उपनिवेशवाद के झुंडे बन गए।

परन्तु इस समय, जब समाजवाद और राष्ट्रीय-मुक्ति आन्दोलन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकास की प्रवृत्तियों को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय कारक बनते जा रहे हैं, स्थिति आमूलचूल रूप से बदल गई है। अब मार मगाए गए किसी उपनिवेश-स्वामी देश द्वारा किसी अन्य उपनिवेशवादी को अपना आसन सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। राष्ट्रीय-मुक्ति आन्दोलन

उपनिवेशवाद को पीछे हटने के लिए विवश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि विश्वव्यापी स्तर पर उपनिवेशवादियों का अधिकार और प्रभाव कम होता जा रहा है, परन्तु यह सोचना गलत होगा कि उपनिवेशवादी शासन की सभी सरहदें और चौकियाँ, सभी अधिकार और सभी सम्भावनाएँ पूर्णतया नव-उपनिवेशवाद, अर्थात् उभनिवेश-रहित उपनिवेशवाद को प्राप्त हो रही हैं। फलतः उपनिवेश-रहित उपनिवेशवाद को पीछे हटने वाला उपनिवेशवाद कहा जा सकता है।

किन्तु, फौजी मुठभेड़ों की भाँति इतिहास के क्षेत्र में भी सामाजिक शक्तियों के संघर्ष में आमतौर पर पीछे हटने का अर्थ यह नहीं होता कि अब आगे घमासान रक्षात्मक लड़ाइयाँ न होंगी, बगली जगी धालें न चली जाएँगी अथवा अस्थायी जवाबी हमले बिलकुल न होंगे। पीछे हटते समय उपनिवेशवाद इन सभी कार्यनीतिक हथकण्डों को घमेल में लाता है। एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में अपनी स्थिति को कायम रखने तथा उसके विस्तार के प्रयास में उपनिवेशवाद किसी भी अनैतिक उपाय को काम में लाने से नहीं हिचकिचाता। वर्तमानकालीन राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का द्रादा उपनिवेशवादियों के केवल प्रत्यक्ष कब्जे के अन्त, अर्थात् औपनिवेशिक शासन-प्रणाली के केवल उन्मूलन से कही अधिक है : उनके अप्रत्यक्ष नियन्त्रण के आधार का अन्त करना, दूसरे शब्दों में, आर्थिक निर्भरता को दूर करना। इस सम्बन्ध में उपनिवेशवाद न केवल राजनीतिक अथवा राजनीतिक-सैनिक दबाव और प्रभुत्व के तरीकों को काम में ला रहा है। वह आर्थिक कदमों की प्रपञ्चपूर्ण प्रणाली का उपयोग करता है और हाल ही में स्वाधीन हुए देशों में विचारधारात्मक तोड़-फोड़ के लिए प्रचार-कार्य शुरू करता है तथा भूतपूर्व उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों में घलन-अलन नेताओं अथवा सम्पूर्ण सामाजिक-राजनीतिक तबकों को कभी-कभी विनीत एवं गुद डंग से, परन्तु बहुत खुलेआम तथा भेदे ढंग में घूस देता है। अब विदेशी भू-भागों को हड़पने और पराधीन देशों में राजनीतिक प्रभुत्व को कायम रखने जैसे तरीके आधुनिक उपनिवेशवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपायों में अपेक्षितः कम महत्व के हैं। इसलिए हालाँकि उपनिवेशवादियों के कब्जे में आज भी कुछ उपनिवेश और प्रदेश हैं, फिर भी आज उपनिवेशवाद के कार्यकलाप का मुख्य क्षेत्र उनकी सीमाओं के बाहर है। पहले की भाँति उसमें एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका शामिल हैं, अन्तर केवल यह है कि अब उपनिवेशवादी इस तथ्य को दृष्टि में रखने के लिए विवश है कि इन तीनों महाद्वीपों के प्रायः सभी देश सार्वभौम राज्य हैं।

वर्तमान पूँजीवादी साहित्य में दो अन्त सम्बद्ध प्रस्थापनाएँ स्पष्टतः देखने में आती हैं, जो मुख्यतः नव-उपनिवेशवाद के सिद्धान्तकारों की धारणाओं का आधार बनती हैं। पहली प्रस्थापना से वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से उपनिवेशवाद अपरिहार्य था और उपनिवेशों, पराधीन तथा परतन्त्र देशों में पश्चिमी राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण सभ्यकारी भूमिका अदा की है। दूसरी प्रस्थापना यह है कि उपनिवेशवाद के साथ ही साम्राज्यवाद भी विनष्ट हो

वर्ग द्वारा किसी अन्य राष्ट्र के शोषण और उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। एशियाई तथा अफ्रीकी राष्ट्रों द्वारा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी उनका आर्थिक शोषण बन्द नहीं हुआ है। शोषण के केवल रूप और तरीके ही बदले हैं। लेनिन ने जोर देते हुए कहा था, न केवल हरेक परस्पर विरोधी सामाजिक ढाँचे, बल्कि पूँजीवाद की प्रत्येक विकास अवस्था के भी औपनिवेशिक शोषण के अपने विशिष्ट ढंग होते हैं।

यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा सागर पार के देशों की भौतिक सम्पदा की सीधी सशस्त्र लूट प्रादिकालीन सचय का समानार्थक था, पर जब पूँजीवाद कायम हो रहा था, उक्त समय बेगार-प्रथा जैसे तरीकों से परन्तु राष्ट्रों को लूटा गया, औद्योगिक पूँजीवाद ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों को अपने उपभोक्ता माल की मण्डियों में परिवर्तित करके उनका शोषण किया, और अन्ततः साम्राज्यवाद के प्रादुर्भाव के साथ उपनिवेश मुख्यतः कच्चे माल के स्रोतों और पूँजी-निवेश के क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण हो गए। लेनिन ने लिखा है—“औपनिवेशिक नीति के अनेक ‘पुराने’ उद्देश्यों के साथ वित्तीय पूँजी ने कच्चे माल के स्रोतों के लिए, पूँजी के निर्यात के लिए, प्रभाव क्षेत्रों के लिए अर्थात् लाभप्रद सौदों, रियायती अधिकारों, इजारेदार मुनाफे आदि के क्षेत्रों के लिए, और अन्त में आर्थिक दृष्टि से आम उपभोगी इलाकों के लिए संघर्ष जोड़ दिया है।”

औपनिवेशिक शोषण के मुख्य तरीकों का यह ऐतिहासिक तत्वादना न केवल उपनिवेश-स्वामी देशों में पूँजीवाद द्वारा विकास की नई अवस्था में सक्रमण वरन् स्वयं उपनिवेशों और अर्द्ध-उपनिवेशों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया को भी प्रतिबिम्बित करता था।

इस बात से एक आधुनिक उपनिवेशवाद को मुख्यतः बिना उपनिवेशों के काम चलाना और सामान्यतया राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के सामने पीछे हटना पड़ रहा है, तत्काल इस नतीजे पर नहीं पहुँच जाना चाहिए कि वह अब पहले की भाँति खतरनाक नहीं है। यह देखते हुए कि वे अपना नियन्त्रण खो रहे हैं, आधुनिक उपनिवेशवादी कठिन क्षणों में सर्वाधिक पाशविक तरीकों अर्थात् फौजों का इस्तेमाल करते हैं। इससे आधुनिक उपनिवेशवाद केवल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ इलाकों के लिए नहीं, बल्कि सामान्यतया सारी दुनिया के लिए गम्भीर सैनिक खतरे का स्रोत बन गया है।

औपनिवेशिक प्रणाली के अवतरण विपटन की स्थिति में उपनिवेशवाद ने राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का सामना करने के लिए बहुशासीय सैनिक राजनीतिक मशीनरी खड़ी की। यह मशीनरी समूची भूतपूर्व औपनिवेशिक दुनिया में काम कर रही है। इसमें बहुदेशीय सैनिक-राजनीतिक गुट, साम्राज्यवादी शक्तियाँ और तीसरी दुनिया के अलग-अलग राज्यों अथवा निजामों के बीच द्विपक्षीय सैनिक गठबन्धन एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में सैनिक (स्थानीय, हवाई और नौमनिक) झुठों का जाल कुछ देशों में बड़ी संख्या में साम्राज्यवादी फौजों की

तैनाती, नव-स्वाधीन देशों के सागरो मे साम्राज्यवादी देशों के नौसैनिक बेड़ों की सतत् उपस्थिति, और कुछ देशों की फौजों का भाड़े की साम्राज्यवादी फौजों में रूपान्तरण शामिल है। नाटो (उत्तराण्टिक सन्धि संगठन), सेन्टो (मध्य सन्धि संगठन), सीटो (दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संगठन), ऐंजुस (आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका का सैनिक गठबन्धन) और ओगस (अमेरिकी राज्यों का संगठन) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय गुट उपनिवेशवाद के सैनिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। मध्य तथा दक्षिण अमेरिका स्थित विदेशी सैनिक अगुओं में अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं जो साफ-साफ लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों की राष्ट्रीय मुक्ति शक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक सैनिक कार्यवाइयों के लिए उन्हें चौकी मानता है।

नवोदित स्वाधीन राज्य की भूमि पर सैनिक अगु स्थापित करने तथा वहाँ अपनी सशस्त्र सेनाएँ तैनात करने का वानूनी अधिकार एक विदेशी शक्ति सामान्यतया सम्बन्धित देश से द्विपक्षीय समझौता करके प्राप्त कर लेती है। इसलिए सही तौर पर यह व्यवस्था पूर्णतया उचित प्रतीत हो सकती है यहाँ तक कि इससे 'समानता के आधार पर फौजी सहयोग' का भ्रम भी पैदा हो सकता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि आधुनिक उपनिवेशवादियों ने दबाव अथवा ब्लैकमेल के जरिए या इसे अधिक प्रीतिवर बनाने के लिए शासक गुट को घूस देकर ही इस प्रकार के सभी समझौते किए हैं।

तथापि देर-सबेर नवोदित राज्य स्पष्टतः यह महसूस करने लगते हैं कि विदेशी सैनिक अगुओं के कायम रहने और विदेशी सैनिकों की उपस्थिति से उनके राष्ट्रीय हितों को काफी आघात पहुँचता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश अधिकाधिक शक्ति के साथ उपनिवेशवाद के इन दुर्गों को उद्ध्वस्त करने और इनके अस्तित्व को मान्यता देने वाली सन्धियों को रद्द करने पर जोर देने लगे हैं।

यदि उपनिवेशिक साम्राज्यों के ध्वंस के इतिहास के पृष्ठों को पलटा जाए तो एक भी ऐसा साल दृष्टि में नहीं आएगा जब किसी नवोदित सार्वभौम राज्य की राष्ट्रीय मुक्ति शक्तियों के विरुद्ध सशस्त्र दण्डात्मक आपरेशन न किया गया हो, सैनिक अभियान न छेड़ा गया हो अथवा सीधा साम्राज्यवादी आक्रमण न किया गया हो। जब कभी राष्ट्रीय प्रान्ति के बाद कोई राष्ट्र आमुल सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सुधार के रास्ते पर बंदम रखता है तो साम्राज्यवादियों का गुस्सा विशेष रूप से भड़क उठता है। उदाहरणार्थ, अरब देशों के विरुद्ध जून, 1967 के इजराइली आक्रमण का यही कारण था। ऐसे लोग भी हैं जो इसे केवल जातीय तथा धार्मिक भावनाओं की टक्कर का रूप प्रदान करना चाहते हैं, जबकि असल बात यह नहीं है। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा समर्थित यह इजराइली आक्रमण मिस्र तथा सीरिया के प्रान्तिवारी जनवादी शासनों के विरुद्ध लक्षित था।

राष्ट्रीय पराधीनता के जुए को उतार फेंकने के बाद जब एक राष्ट्र तत्काल अपने जीवन को समाजवादी ढंग में पुनर्निर्मित करने लगता है तो इस बात में

आधुनिक उपनिवेशवादी आभवबलता हो उठते हैं। इसका प्रमाण पाने के लिए क्रान्तिकारी क्यूबा के घटना-क्रम पर दृष्टिपान करना ही पर्याप्त है, जिस पर सन् 1959 में घटिस्ता की तानाशाही का तख्ता उलटने के बाद से अमेरिका लगातार अपना दबाव डालता और उसके विरुद्ध आक्रमण करता रहा है। बीसवीं सदी के सभी औपनिवेशिक युद्धों में सबसे अधिक पाशविक और जर्मनाक युद्ध वह था, जिसे अमेरिका साम्राज्यवादियों ने वियतनाम की वीर जनता के विरुद्ध छेड़ा था। वियतनाम की भूमि पर अमेरिकी साम्राज्यवाद पररत शासन का समर्थन करने के इरादे की 'निर्दोष' धोखाधियों के साथ शुरू होने वाली नव-उपनिवेशवादी नीति अक्सर राष्ट्र की देशभक्त शक्तियों के विरुद्ध आकायदा सैनिक कार्यवाही और उसमें आसपास के इलाकों के भी उलझा लिए जाने का रास्ता खोल देती है, जिससे दुनिया की सुरक्षा और शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक या नव-उपनिवेशवाद का सैनिकतन्त्र प्रायः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भूमि पर रक्तपात मचाता है। वर्तमान समय में साम्राज्यवादियों द्वारा यज्ञ-तण्डुल शुरू किए गए औपनिवेशिक युद्ध विशुद्ध स्थानीय महत्त्व के मामले नहीं रह गए हैं। साम्राज्यवादी आक्रमण के खतरे से पूर्ववत् अस्त एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश समान हितों द्वारा समाजवादी देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। इसी कारण इस समय किसी भी औपनिवेशिक युद्ध से विश्वव्यापी युद्ध शुरू हो सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध हो रहा दृढ़ संघर्ष साथ ही विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिए भी संघर्ष है।

आधुनिक या नव-उपनिवेशवाद खुले आक्रमण के अलावा नव-स्वाधीन देशों तथा राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के अन्य तरीकों और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन पर दबाव डालने की अन्य रीतियों को भी काम में लाता है।

नव-उपनिवेशवाद नवोदित सार्वभौम राज्यों को आर्थिक नाकेबन्दी करके बहुधा अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करता है। मिस्र को तेल की सप्लाई बन्द करके तथा मिस्री कपास की खरीद पर रोक लगाकर इस देश को स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का इरादा त्याग देने के लिए विवश करने के प्रयास में साम्राज्यवादियों ने सन् 1956 में उस पर इस प्रकार का दबाव डाला था। सन् 1959 में फ्रांस ने अपने मूलपूर्व उपनिवेश बिनी के विरुद्ध आर्थिक नाकेबन्दी की। जिसने अफ्रीका में विघटित फ्रांसीसी साम्राज्य का स्थान ग्रहण करने वाले नए औपनिवेशिक संगठन में शामिल होने से इन्कार कर दिया था।

अनुदार और ऋण भी साम्राज्यवादियों द्वारा नवोदित सार्वभौम राज्यों की नीतियों को प्रभावित करने का एक और साधन है। सहायता-कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई धन-राशि अधिकांश मामलों में इन देशों के सत्ताहूढ़ हल्कों को राजनीतिक घूस देने के अनिरिक्त और कुध नहीं है। साक्षणिक बात यह है कि अमेरिका द्वारा विकासमान देशों को सहायता के रूप में दी गई धन राशि का करीब 80% ऐसी

सरकारों को दिया गया है, जो द्विपक्षीय समझौतों के अन्तर्गत तथा विविध सैनिक गुटों की सदस्यता के फलस्वरूप उसके सैनिक तथा राजनीतिक संघाती है। दूसरी ओर, आधुनिक उपनिवेशवादियों की आकांक्षाओं के प्रतिकूल नीतियों का अनुसरण करने वाले नवोदित स्वाधीन राज्य को 'दण्डस्वरूप' ऋण तथा अनुदान देना बन्द कर दिया जाता है तथा लागू आर्थिक समझौतों के अन्तर्गत मिलने वाली सप्ताई भी रोक दी जाती है।

नवोदित स्वाधीन राज्यों में जहाँ भी सम्भव होता है, उपनिवेशवादी आशाकारी कठपुतली शासन कायम करते हैं और अपने समर्थकों को राष्ट्रपति तथा मन्त्रियों के आसन पर बिठाते हैं। ऐसी कठपुतलियाँ अपने मालिकों की इच्छानुसार सर्वथा जनवाद-विरोधी नीतियों का अनुसरण करती हैं। फलतः कभी-कभी तो उपनिवेशवादियों की समीनें और घूस भी उन्हें धराशाही होने से नहीं बचा पाती हैं, जैसा कि सन् 1960 में दक्षिण कोरिया में सिंगमानरी की तानाशाही के साथ और इसके दो साल बाद दक्षिण वियतनाम में 'गो दिन दियेम' गुट के साथ हुआ। यही दृश्य इराक के नुरी अल-सईद (1958), क्यूबा के बतिस्ता (1959), तुर्की के मेदरीज (1960), डोमोनिकन गणराज्य के त्रुजिल्लो (1961), और कांगो (ब्राजविले) के फुलबर्ट योलोमु (1963) जैसे साम्राज्यवादी समर्थकों का हुआ, जो जन-आक्रोश की लहर में बह गए। फिर भी, साम्राज्यवादी एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में यत्र-तत्र अपने दलालों को नेतृत्वकारी पदों पर बनाए रखने में सफल रहे हैं। कठपुतली सरकारें कायम करने की इन औपनिवेशिक नीति के फलस्वरूप अनेक प्रतिक्रियावादी राज्य विप्लव हुए हैं।

सशस्त्र आक्रामक कार्यवाहियाँ, आर्थिक नाकेबन्दियाँ और जरखरीद कठपुतली सरकारें, ये सभी बातें नवोदित स्वाधीन देशों के राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हैं, और प्रासंगिक केवल मेहनतकश लोगों के ही नहीं, बल्कि स्थानीय पूंजीपति वर्ग के भी हितों के विरुद्ध हैं। दूसरे शब्दों में, आधुनिक या नव-उपनिवेशवादियों द्वारा अपनाई गई लुटेरू नीति का समर्थन भूतपूर्व उपनिवेशों तथा अर्द्ध-उपनिवेशों के मुट्ठी भर सामन्ती और फौजी-जीकरशाही तत्त्व ही करते हैं, क्योंकि वह केवल उन्हीं के रुझानों के अनुरूप हो सकती है।

प्रश्न पैदा होता है कि क्या सशस्त्र आक्रमण जैसे उपनिवेशवाद के हिंसात्मक रूप इसकी शक्ति के छोटक हैं अथवा इसकी कमजोरी के? निश्चयसे, इसका मतलब साम्राज्यवादियों की सैनिक शक्ति को घटाना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके पास आधुनिकतम हथियारों से लैस बड़ी-बड़ी सेनाएँ और समुद्री बेड़े हैं। अतः इस प्रश्न का सम्बन्ध भूतपूर्व औपनिवेशिक साम्राज्य में साम्राज्यवाद की वर्तमान स्थिति की दृढ़ता है।

हम इस पहलू की ध्यानहीन बर चुके हैं और हमने इसे गिद्ध भी कर दिया है कि विश्वव्यापी स्तर पर तथा इतिहास की दृष्टि से उपनिवेशवाद पीछे हट रहा है। हम इस बात की ओर भी संकेत कर चुके हैं कि जब उपनिवेशवादी यह देखने हैं

कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है तो वे अपनी सेनाओं का सहारा लेते हैं। प्रथम हम इस दावे के अर्थ को कुछ अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं, जिसका सम्बन्ध उन देशों में उपनिवेशवाद के सामाजिक आधार से है, जिन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है अथवा जो प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

जब भी साम्राज्यवादी स्थानीय प्रतिक्रियावादियों के छोटे चाटुकार समूह का गमर्पण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, देश में तीव्र जन-आन्दोलन का तूफान भड़क उठता है, जिसके फलस्वरूप उपनिवेशवादी जवाबी प्रहार के रूप में सशस्त्र कार्यवाही का सहारा लेते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी कार्यवाहियों का कोई फल नहीं होता, क्योंकि उनके विरोध में सारी जनता खड़ी होती है। दक्षिण विषयनाम में इसी प्रकार की स्थिति का विश्लेषण करते हुए अमेरिकी सिनेटर जे. विलियम फुलब्राइट ने अपनी एक पुस्तक में अमेरिका की विषयनाम सम्बन्धी कार्यवाही को नैराशपूर्ण जोखिम बताया था और अपने देशवासियों से "सच्ची राष्ट्रीय क्रांति को कुचलने का निर्मम और असम्भवप्रायः कार्यभार हाथ में न लेने" का अनुरोध किया है। संजीदा विचारों वाले दूसरे भी बहुत से प्रमुख पूँजीवादी नेता आधुनिक उपनिवेशवादियों द्वारा शुरू की गई दुस्साहसिक सैनिक कार्यवाहियों के इस मूल्यंकन से सहमत हैं।

अतः हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है—“आधुनिक उपनिवेशवादी सशस्त्र हस्तक्षेप तथा बल-प्रयोग के अन्य तरीकों का सहारा इसलिए नहीं लेते कि वे अक्षिणाली हैं। उल्टे, इससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उनकी स्थिति की आम कमजोरी प्रकट होती है और उपनिवेशवाद के अनिवार्य विनाश का संकेत होता है।”

साम्राज्यवादी हल्कों के अनेक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों ने स्वाधीन देशों में अपनी नीतियों के लिए सामाजिक आधार को विरतृत करने का महत्त्व महसूस कर लिया है। उनके मतानुसार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पश्चिमी राष्ट्रों का यही मुख्य दीर्घकालिक अथवा रणनीतिक उद्देश्य होगा चाहिए। वे आधुनिक उपनिवेशवाद के 'बठोर' तरीकों की आलोचना में समय-समय पर यही दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे दीर्घकालिक, विनम्र और सुव्यवस्थित तरीके से स्वाधीन राष्ट्रों को लुप्त करने की युक्ति अपनाने और तानाशाही तरीकों का परित्याग करने का सुझाव प्रस्तुत करते हैं। उनके मतानुसार इस प्रकार की युक्ति का अन्तिम लक्ष्य भूतपूर्व उपनिवेशों तथा अर्द्ध-उपनिवेशों में ऐसे बड़े जनसमूहों और सार्वजनिक संगठनों की पैदा करना है जिनकी विचारधारा एवं राजनीतिक सद्भावना 'पश्चिमी जीवन-पद्धति', अर्थात् साम्राज्यवाद की ओर उन्मुख हो। इस ढंग से इस नीति के पोषकों को स्वाधीन देशों के जिम्मेदार सामाजिक समुदायों के साथ टिकाऊ मैत्री स्थापित करने तथा विभिन्न कठपुतली सरकारों के साथ तकलीफदेह और शर्मनाक साँझाँठ को खत्म करने में सक्षम हो जाने की आशा है।

जिन विकासमान देशों में बड़ा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग है, वहाँ साम्राज्यवादी स्पष्टतः उसी पर भरोसा करते हैं। किन्तु भूतपूर्व औपनिवेशिक दुनिया में ऐसे देशों

की संख्या बहुत कम है, और आधुनिक उपनिवेशवादी अपनी समस्या का समाधान इसी में देखते हैं कि जहाँ ऐसा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग पहले से नहीं है, वहाँ उसे अस्तित्व में लाया जाए। दूसरे शब्दों में, वे भूतपूर्व उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों में पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों को 'रोपना' चाहते हैं।

नव-उपनिवेशवादियों ने जो सामाजिक-आर्थिक तरकीब अपनायी है, उसका यही सारतत्त्व है, उसका अन्तिम लक्ष्य है। पूँजीवादी प्रणाली के अन्तर्गत स्वाधीन देशों को बनाए रखना, जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय इजारेदार पूँजी उनका शोषण कर सकती है और विकास के गैर-पूँजीवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से उन्हें रोकना।

इस रणनीति के सिद्धान्तकार यह भी बताते हैं कि कैसे यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वे सम्बन्धित देशों को कुछ रियायतें प्रदान करने, जैसे तटस्थता और सैनिक गुटों से अलग रहने की उनकी नीतियों को बर्दाश्त करने, उनके द्वारा उद्घोषित समाजवादी सिद्धान्तों तक की आलोचना न करने की और इस तरह भूतपूर्व उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों के पूँजीपति तथा निम्न पूँजीपति वर्गों को खुश करने का सुभाव प्रस्तुत करते हैं। विकासमान देशों को 'सहायता' प्रदान करना इस नव-उपनिवेशवादी रणनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है।

नव-उपनिवेशवादी 'सहायता' को ही भूतपूर्व औपनिवेशिक दुनिया में इस समय हो रही तीव्र सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का सर्वोत्कृष्ट तरीका मानते हैं।

साम्राज्यवादी कठपुतली शासनो को वित्तीय भवलम्ब देने के लिए बहुधा अनुदानों और ऋणों का उपयोग करते हैं और इस प्रकार दीर्घकालिक दाव-पेच द्वारा अपेक्षित आवादी के व्यापक हिस्सों, विशेष रूप से पूँजीपति और निम्न-पूँजीपति वर्गों की जगह, ऊपरी प्रतिश्रियावादी सामन्ती तथा सैनिक तबकों से दोस्ती को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह सही है। मगर साथ ही यह भी सही है कि 'सहायता' को एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय धूस के रूप में इस्तेमाल करने के प्रतिरिक्त साम्राज्यवाद प्राप्तकर्ता देशों पर सख्त राजनीतिक अथवा सैनिक शर्तों को बिना उन्हें अधिकाधिक अनुदान तथा ऋण प्रदान करता जा रहा है। हाल के वर्षों में यह बात विशेष रूप से प्रकट हुई है और मुख्यतः इसका कारण समाजवादी राज्यों के साथ स्वाधीन देशों का बढ़ता हुआ सहयोग है। तथ्य यह है कि साम्राज्यवादी अपनी लूट पर अंकुश लगाने तथा अपने भूतपूर्व उपनिवेशों एवं अर्ध-उपनिवेशों को रियायतें प्रदान करने के लिए विवश है, क्योंकि ये देश सार्वभौम राज्य बनने के बाद समान अधिकारों तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर समाजवादी देशों से आवश्यक ऋण, मशीनें और उपकरण प्राप्त सकते हैं। फलतः हाल के वर्षों में पश्चिमी राष्ट्रों ने बहुधा अपेक्षाकृत कम व्याज पर ऋण देना और पिछले ऋणों के मुग्तान की अवधि लम्बा करना उचित समझा है। लेकिन इसके बदले में ऋण देने वाले साम्राज्यवादी राष्ट्र एक शर्त रखते हैं और वह यह है : पूँजीवादी धर्मव्यवस्था को विवर्गित करने

और स्थानीय पूंजीपति वर्ग को सुदृढ़ बनाने के निमित्त ऋण पाने वाले देशों को पूंजीवादी सुधारों का कार्यक्रम अवलम्बन में लाना चाहिए।

आधुनिक उपनिवेशवाद के रणनीतिज्ञ विकासमान देशों के लिए 'तकनीकी सहायता' पर अपना विशेष ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में साम्राज्यवादी विचारधारात्मक प्रसार के लिए 'तकनीकी सहायता' एक आवरण है, जिसके पीछे स्वाधीन देशों के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रतिक्षण होता है और फिर वहाँ साम्राज्यवादी राज्यों से विशेषज्ञ, सलाहकार तथा प्रशिक्षक भेजे जाते हैं। वस्तुतः एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के नवोदित स्वाधीन देशों में तकनीशियन, डाक्टरों, शिक्षकों, अर्थशास्त्रियों और प्रशासकीय अधिकारियों की बहुत कमी है। औपनिवेशिक शासन-प्रणाली की यह सबसे निकृष्ट विरासत है। इसी लक्ष्य से वे विकासमान देशों के युवक-युवतियों को अपने कालेजों तथा विश्व-विद्यालयों में दाखिला देते हैं। आधुनिक उपनिवेशवाद एशियाई, अफ्रीकी, और लेटिन अमरीकी राष्ट्रों को इस प्रकार अभिभूत कर लेने, स्वाधीन देशों के परासम्भव अधिक से अधिक लोगों के मन में पूंजीवादी प्रणाली और पश्चिमी जीवन-पद्धति के प्रति प्रशंसा भाव भरने का प्रयास करता है। अपने सलाहकारों और विशेषज्ञों के जरिये काम करते हुए आधुनिक उपनिवेशवादी आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए नवोदित स्वाधीन राज्यों पर पूंजीवादी परिपाटी थोपने की कोशिशें कर रहे हैं।

साम्राज्यवादी विचारधारात्मक प्रसार का एक रूप होने के नाते 'तकनीकी सहायता' स्वाधीन देशों में आधुनिक उपनिवेशवादियों द्वारा चलाये जाने वाले सतत प्रचार से भिन्न है, जिसमें पश्चिमी, अर्थात् पूंजीवादी जीवन-पद्धति की तारीफ करने वाले साहित्य, साम्राज्यवादी राष्ट्रों की नीतियों की प्रशंसा करने वाले रेडियो प्रसारणों और प्रचार के अन्य परम्परागत साधनों का व्यापक उपयोग किया जाता है। यह प्रचार किसी एक विकासमान देश का नहीं, अपितु एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के सभी देशों को समान रूप से सम्बोधित करता है। भूतपूर्व औपनिवेशिक दुनिया में नव-उपनिवेशवादियों का लक्ष्य स्पष्ट है वे अपने समर्थकों की एक जमात कायम करने में लगे हैं। प्रत्येक स्वाधीन देश में नव-उपनिवेशवाद की रणनीति का उद्देश्य वहाँ की सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं तथा वहाँ के लोगों के बौद्धिक व मानसिक विकास पर साम्राज्यवादी नियन्त्रण स्थापित करना है। स्वाधीन देशों में पूंजीवादी प्रणाली कायम करने के लिए निर्धारित इस कार्यक्रम की अन्तिम लक्ष्य उनमें बसे लोगों के राष्ट्रीय हितों के संरक्षा प्रतिकूल है, जो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के वर्तमान दौर में अधिकाधिक रूप से विकास के गैर-पूँजीवादी रास्ते को पसन्द करते हैं।

आज के उपनिवेशवादियों के व्यवहार में विरोधाभास है। कुछ अवस्थाओं में वे नवोदित सार्वभौम राज्यों के प्रति सहिष्णुता की भावना प्रदर्शित करते हैं और उनकी माँगों भी स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु कुछ अन्य अवस्थाओं में नृशंस दमन के साथ उन पर दृढ़ पड़ते हैं। सच बात तो यह है कि इसमें कोई असंगति है भी

नहीं। नव-उपनिवेशवादी रणनीति और दैनिक कार्यनीति दोनों स्वाधीन देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की ओर लक्षित है। केवल इस हस्तक्षेप के रूप बदल जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिन अवस्थाओं में आधुनिक उपनिवेशवाद बल-प्रयोग की धमकी नहीं देता, उनमें भी स्वाधीन देशों के लिए इसका सभावित खतरा कम नहीं होता। जब नव-उपनिवेशवाद बहुत ही नेक रूप में प्रकट होता है, उस समय भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है विदेशी राजनीतिक बन्धन से मुक्त लोगों पर पूँजीवादी शोषण के जुए को लादना।

आज के नव-उपनिवेशवाद के स्वरूप की छानबीन समाप्त करने के पहले यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वह एक निश्चित आर्थिक आधार पर निर्मित ऊपरी ढाँचा है। हमने इस परिशीलन में विश्व पूँजीवादी प्रणाली में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की हीन और शोषित स्थिति के मुख्य लक्षणों की छानबीन की है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त और इजारेदार पूँजी द्वारा एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमरीकी देशों के जनबल तथा प्राकृतिक साधनों का शोषण ही स्पष्टतः वह आर्थिक आधार है, जिस पर नव-उपनिवेशवाद टिका हुआ है। यही वह आधार है, जिस पर सैनिक गुटों तथा संधियों, खुले हस्तक्षेप, कठपुतली सरकारों के आरोपण, कष्टदायक ऋण-नीति, स्थानीय पूँजीपति वर्ग को प्रलोभित करने की चाल आदिकी अधिरचना अवलम्बित है।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देशों में साम्राज्यवाद आज भी आर्थिक दृष्टि से काफी गहरे बैठा हुआ है। इन देशों का प्रायः दो-तिहाई विदेशी व्यापार विकसित पूँजीवादी राज्यों के साथ होता है और भूतपूर्व उपनिवेशों तथा अर्ध-उपनिवेशों में विदेशी इजारेदारियों का प्रत्यक्ष पूँजी-निवेश दसियों अरब डॉलर का है। साम्राज्यवादी सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों के मामले में नव-स्वाधीन देशों का राष्ट्रीय बर्ज भी विपुल है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका में आर्थिक प्रसार के इन मुख्य रूपों का इस्तेमाल करते हुए साम्राज्यवाद ने भूतपूर्व उपनिवेशों तथा अर्ध-उपनिवेशों के विरुद्ध राजनीतिक, सैनिक और विचार-धारात्मक हमले में सफलताएँ पाने की सम्भावना प्राप्त की है।

प्रश्न उठता है कि स्वाधीन देशों के भविष्य पर नव-उपनिवेशवादी दबाव का प्रभाव कैसे पड़ता है? उपनिवेशवाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के देशों का सबसे बड़ा शत्रु रहा है और है। हम दिखायेंगे कि जिन-जिन ठोस रूपों में वह अपने को जाहिर करता है। निश्चय ही सबसे पहले आर्थिक शोषण में, जितने स्वाधीन देश आर्थिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक अपने प्राकृतिक साधनों के बड़े भाग से वंचित हो जाते हैं। साम्राज्यवादी आक्रामक नीति स्वाधीन देशों की राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में एक और बाधा उत्पन्न करती है? सैनिक व्यय की पुति के लिए काफी विनियोजन अपेक्षित है। ऐसा इसलिए होता है कि या तो साम्राज्यवादी अपने सैनिक गुटों में शामिल देश से ऐसे बंदमों की प्रत्यक्ष माँग करते हैं, अथवा सीमाओं पर पैदा हुई खतरनाक स्थिति के कारण शान्तिप्रिय देश अपनी प्रारिक्षा

व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विवश हो जाता है। साम्राज्यवाद भूतपूर्व उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों की सामाजिक प्रगति का भी शत्रु है। कुछ अवस्थाओं में वह उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के लिए नृशंस कदम उठाता है और अंदरूनी सगौनों के बल पर सामन्ती-जमींदारी तबके के प्रतिश्रियावादियों को सत्ताहीन बनाता है। अन्य अवस्थाओं में वह निजी पूँजी को अपना पूरा समर्थन प्रदान करता है तथा ऐसे समय उसकी स्थिति मजबूत करने में जुटा रहता है। जब सामाजिक आर्थिक सुधार पूँजीवाद-विरोधी रूप ले चुके हैं। उपनिवेशवादी विचारधारात्मक प्रसार का लक्ष्य होता है नव-स्वाधीन देशों की जनता की देशभक्तिपूर्ण और क्रान्तिकारी भावनाओं को कुचलना तथा पूँजीवादी व्यवस्था एवं 'पश्चिमी जीवन-पद्धति' की 'श्रेष्ठता' के प्रति विश्वास को बढ़ावा देना।

फिर भी घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक उपनिवेशवादियों की सफलताएँ सामान्यतया टिकाऊ नहीं होती। आधुनिक उपनिवेशवाद का कोई ऐतिहासिक भविष्य नहीं रहा है। दुनिया का वर्तमान शक्ति-सन्तुलन साम्राज्यवादी स्वैच्छाचारिता के क्षेत्र को अधिकाधिक सीमित करता जा रहा है। जब साम्राज्यवादी मनमाने ढंग से राष्ट्रों के भविष्य को गढ़ सकते थे, वे दिन लद गए हैं। आज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है कि राष्ट्रीय मुक्ति शक्तियाँ उपनिवेशवादियों पर एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो गई हैं। नव-उपनिवेशवाद की बहुत सी योजनाएँ यथार्थ में उसकी विफलताएँ बन जाती हैं। यह अपने न्यायोचित ध्येय के लिए सधरंतर, राष्ट्रीय मुक्ति शक्तियों द्वारा प्रदर्शित दृढ़ता तथा स्थिरता पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, स्वाधीन देशों को दी जाने वाली साम्राज्यवादी 'सहायता' को ही लें। नव-उपनिवेशवादी रणनीतिज्ञों की आशा है कि प्रचुर ऋणों और अनुदानों से नवोदित सार्वभौम राज्यों को अन्ततः अपने पक्ष में कर लिया जाएगा और साम्राज्यवाद के पक्ष में उनका अभिमुखीकरण तथा पूँजीवादी पथ से उनका विकास सुनिश्चित हो जाएगा। परन्तु इसका मतलब यह नहीं होता कि वे अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। नवस्वाधीन देश अपनी सार्वभौमता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए साम्राज्यवादी सरकारों द्वारा प्रदत्त धन-राशि को नव-उपनिवेशवादियों के प्रवेश का साधन बनने देने की अपेक्षा अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में समर्थ हो सकते हैं।

वर्तमान ऐतिहासिक परिवेश में, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन—बशर्ते कि वह शक्ति, समाजवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग की शक्तियों के साथ मिलकर संघर्ष कर रहा हो—न केवल नव-उपनिवेशवाद के दबाव का सामना करने में, बल्कि उसके विरुद्ध सफल संघर्ष करने में भी सक्षम है।

आज पूँजीवाद लेसक भी नव-उपनिवेशवाद के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए विवश है। इस सम्बन्ध में उनसे एक का कहना इस प्रकार है : अपने वनासिकल रूप में नव-उपनिवेशवाद का अर्थ यह है कि अभी ऐसे लोग हैं, जो स्पष्टतः उपनिवेशवाद की पुरानी प्रणाली का परित्याग करने के इच्छुक होते हुए

भी सामान्यतया आर्थिक ढंग के नये पराश्रित सम्बन्धों को जिन्हें 'प्रच्छन्न उपनिवेशवाद' कहा जाता है—कायम करने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता यह है कि अफ्रीका में नव-उपनिवेशवाद बड़े पैमाने पर अपना कार्य कर रहा है। निःसन्देह, कुछ ऐसे पूँजीवादोत्प्रेषक भी हैं, जो तथ्यों के प्रतिबल यह दावा करते हैं कि नव-उपनिवेशवाद जैसी कोई चीज नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्रों का अन्य उपायो से साम्राज्यवादी शोषण जारी रखने का ही दूसरा नाम नव-उपनिवेशवाद है। आधुनिक पूँजीवाद के ढाँचागत परिवर्तनों से सम्बद्ध आन्तरिक कारकों और दो निर्णायक बाह्य कारकों—विश्व समाजवादी प्रणाली की बढ़ती हुई शक्ति और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का उभार के प्रभाव से शोषण के रूप और तरीके बदल गए हैं। साम्राज्यवादी अपनी नव-उपनिवेशवादी नीति का इस्तेमाल करते हुए जनवादी राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को सामाजिक अन्तर्य से वंचित करने और नवोदित स्वाधीन राज्यों को समानाधिकार दिए बिना उन्हें पूँजीवादी दायरे में बताए रखना चाहते हैं। आधुनिक उपनिवेशवाद का मुख्य स्तम्भ समुक्त राज्य अमरीका का साम्राज्यवाद है, जिसका अपनी राष्ट्रीय मुक्ति के लिए सघर्षरत लोगों के वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय पुलिसमैन और जल्लाद के रूप में सर्वत्र पर्दाफाश हो चुका है। अमरीकी साम्राज्यवाद के हिमायती प्रायः एशिया और अफ्रीका में समुक्त राज्य अमरीका के विशेष हितों की चर्चा करते हैं, जो मानो यूरोपीय औपनिवेशिक राष्ट्रों के हितों से भिन्न हैं। वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में अमरीकी गतिविधियाँ केवल कम्युनिज्म का प्रसार 'रोकने' की तथाकथित नीति की आवश्यकताओं से निर्दिष्ट हैं।

नव-उपनिवेशवादी प्रचार का मुख्य लक्ष्य है उपनिवेशवादी का अचिंत्य सिद्ध करना, उत्पादन के पूँजीवादी ढंग और पूँजीवादी जीवन-पद्धति को कायम रखना और यह 'सिद्ध करना' कि पिछड़े हुए राष्ट्रों के पुनरुद्धार में केवल पूँजीवाद ही समर्थ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के नव-उपनिवेशवादी सिद्धान्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें न केवल पूँजीवादी पश्चिम में बल्कि विकासमान देशों के कुछ हल्कों में भी स्वीकार कर लिया गया है। उपनिवेशवाद को उचित बताने के अपने प्रयास में कुछ पूँजीवादी सिद्धान्तकार एशियाई और अफ्रीकी देशों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का दोष खुद वहाँ के लोगों पर मढ़ते हैं।

औपनिवेशिक युद्धों और सैनिक गुटों, साजिशों तथा आतंक, तोड़फोड़कारी कार्यवाइयों एवं आर्थिक दबावों व घूस के जरिए साम्राज्यवादी स्वाधीन देशों पर अपना प्रभुत्व कायम रखना अथवा इन देशों द्वारा प्राप्त स्वाधीनता को केवल दिसावे की बात बनाना या उन्हें उससे वंचित करना चाहते हैं। इसलिए नवोदित स्वाधीन राज्यों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार है नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, जो साथ ही उनके स्वतन्त्र विकास राष्ट्रीय तथा सामाजिक प्रगति का मयर्प भी है।

वर्तमान युग और राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन

वर्तमान युग की एक विशेषता राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलनों का तूफानी विकास है जिनके प्रभाव से विश्व की औपनिवेशिक प्रणाली ध्वस्त होनी जा रही है। जब पुराने औपनिवेशिक साम्राज्यों के ध्वंसावशेषों पर स्वाधीन राष्ट्रों का आविर्भाव हुआ

3. स्वाधीन राज्यों के आविर्भाव ने शेष पराधीन और अर्द्ध-पराधीन राष्ट्रों की मुक्ति की गति तीव्र हो जाती है। इस बात का भी संकेत है कि राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन नए दौर में प्रविष्ट हो गया है और अब सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।

जिन देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है अथवा प्राप्त कर रहे हैं, उनके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनमें राजनीतिक स्वाधीनता का प्रसार और सुदृढीकरण नितान्त आवश्यक है जो वस्तुतः सच्ची स्वतन्त्रता की अपरिहार्य शर्त है। इसके साथ ही पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता सामाजिक-आर्थिक सुधारों की गहराई और व्यापकता का नतीजा होनी है। जिस प्रकार विश्व की दो प्रणालियों के सम्बन्धों में आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता का प्रमुख स्थान है, उभी प्रकार राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन के वर्तमान दौर में सामाजिक-आर्थिक हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी कारण चीनी विद्वान्तकार मतल है जो एक ओर अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास तथा अपनी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नवोदित सार्वभौम राज्यों के प्रयासों और दूसरी ओर साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष के बीच असंगति देखने का दावा करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास को राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन के ध्येयों का 'परित्याग' समझते हैं। उसके विपरीत सामाजिक-आर्थिक विकास की समस्याओं की उपेक्षा का अर्थ है हाल ही में प्राप्त स्वतन्त्रता को नमजोर करना और साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन पर प्रहार सुगम बनाना।

4. मौजूदा राष्ट्रीय मुक्ति-क्रान्तियाँ अपने स्वरूप की दृष्टि से अधिक गहन हो गई हैं। एक समय था जब पूँजीवादी-जनवादी क्रान्तियों के अलावा वे और कुछ नहीं थी और ईरान तथा तुर्की की भाँति उनसे केवल पूँजीवादी विकास का पथ ही प्रशस्त होना था। परन्तु अब अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में वर्गगत शक्तियों के परिवर्तित सम्बन्धों की वजह से साम्राज्यवाद-विरोधी राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्तियों का समाजवादी क्रान्तियों के रूप में तीव्र विकास सम्भव हो गया है।

वर्तमान समय में दोनों प्रकार की क्रान्तियाँ—राष्ट्रीय मुक्ति और समाजवादी एक दूसरे के निकट आती जा रही हैं। राष्ट्रीय मुक्ति-क्रान्तियाँ शुरू से ही अधिकांशतः न केवल साम्राज्यवादी और सामन्ती व्यवस्था, बल्कि एक प्रकार से पूँजीवाद के विरुद्ध भी बुनियादी रूप में उसी शत्रु के खिलाफ लक्षित हैं जिसके विरुद्ध मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी क्रान्ति लक्षित है।

5. सामाजिक राष्ट्रीय मुक्ति-क्रान्तियाँ संघर्ष के विभिन्न साधनों और रूपों का उपयोग करती हैं।

अपने देश की ठोस-स्थिति और राष्ट्रीय क्रान्ति की अवस्था की दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक जनता संघर्ष के किसी विशेष रूप को अपनाती है। राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने और इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने की ओर लक्षित साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में सशस्त्र विद्रोह सहित सभी तरीके अपनाए जाते हैं।

6. यदि हम राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन के इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिपान करें तो देखेंगे कि कई भूतपूर्व उपनिवेशों ने बिना सशस्त्र संघर्ष के अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की है। राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन के वर्तमान दौर में, जब सारे एशिया और अफ्रीका नवोदित स्वाधीन राज्यों का आविर्भाव हो रहा है और उनमें से अनेक प्रगतिशील सामाजिक-आर्थिक सुधारों का मार्ग अपना रहे हैं, निष्पक्ष दृष्टिकोण से सशस्त्र संघर्ष का आह्वान या तो विकसित देशों सहित इन देशों की वर्तमान सरकारों के विरुद्ध विद्रोहों का औचित्य सिद्ध करने अथवा क्रान्तिकारी प्रक्रिया को 'सीत्र गति प्रदान करने' के उद्देश्य से विकासमान देशों और भूतपूर्व औरानिवेशिक शक्तियों के बीच सशस्त्र संघर्ष भड़काने के लिए लक्षित है। इस प्रकार के 'क्रान्तिकारी' हथ से इन में विकासमान साम्राज्यवाद-विरोधी समुक्त मोर्चों में केवल दगर पैदा हो सकती है, राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन को गम्भीर क्षति पहुँच सकती है और इसका आगे का विकास अवरुद्ध हो सकता है।

राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन की कुछ नई विशेषताएँ, आज की दुनिया में अपनी विशेष भूमिका और महत्त्व को प्रकट करती हैं।

राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में सेना की भूमिका (सेना और राजनीति)

राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष और राजनीति के सन्दर्भ में सेना की भूमिका के बारे में प्र. इस्केंदेरोव के विचार संक्षेप में इस प्रकार हैं—

हाल में सेना ने एशिया और अफ्रीका के कई नवोदित स्वाधीन राज्यों की राजनीतिक घटनाओं में प्रमुख भाग लिया है। इस वस्तुगत विकास से कई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं जिनका सैद्धान्तिक विश्लेषण राष्ट्रीय तथा सामाजिक प्रगति के लिए और साम्राज्यवादी तथा आन्तरिक प्रतिक्रिया के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को एकजुट करने के तरीके व उपाय निश्चित करने की दृष्टि में व्यावहारिक महत्त्व का है उदाहरण के लिए, इन समस्याओं का सम्बन्ध राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में सेना की भूमिका और विकासमान देशों के राजनीतिक कार्यकलापों पर इसके प्रभाव तथा जन-समुदाय एवं उसके संगठनों द्वारा संघर्ष के महत्त्व से है।

राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष में सेना की भूमिका के बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ लेखक इसकी कोई भी प्रगतिशील भूमिका नहीं मानते और सैनिक विद्रोह के फलस्वरूप कायम किसी भी सरकार को प्रतिगामी सैन्यवादी बताते हैं। दूसरे लेखक राष्ट्रीय मुक्ति-क्रान्ति का नेतृत्व करने में सक्षम सेना को लगभग एवमात्र राष्ट्रीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी यह मत प्रकट किया जाता है कि जनसमुदाय के समर्थन और प्रगतिशील राजनीतिक पार्टी के अस्तित्व के बिना भी सेना स्वाधीन देश के राजनीतिक और आर्थिक विकास का पूरा दायित्व ग्रहण करने में सक्षम है।

इनमें से कोई भी विचार सही नहीं है क्योंकि किसी भी अन्य सामाजिक व्यवहार की भाँति राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की भूमिका के मूल्यांकन के लिए वर्गगत

दृष्टिकोण प्रप्रेक्षित है। समाज में उसी स्थिति सम्बन्धित समाज के स्वरूप, वर्गगत एवं राजनीतिक शक्तियों के सन्तुलन और शान्तिकारी आन्दोलन के प्रसार तथा तीव्रता पर अवलम्बित है। किसी भी वर्गगत समाज में श्रमिकों का शान्तिकारी सघर्ष अनिवार्यतः सेना को राजनीतिक दबण्डर से खींच लेता है। लेनिन ने लिखा था—
“सेना न कभी तटस्थ रह सकती है, न कभी थी और न कभी रहेगी।”

एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का विकास यह सिद्ध करता है कि तटस्थ रहने की जगह सेनाएं अपने-अपने देश की राजनीतिक सुरगर्भी में सक्रिय भाग लेती हैं तथा अक्षर घटनाक्रम के विकास में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। इसके अनेक कारण हैं—

1. जहाँ पूँजीवादी समाज के बुनियादी वर्ग अपर्याप्त रूप में विकसित होते हैं, वहाँ गैर-मैनिक तथा मैनिक बुद्धिजीवी समुदाय जैसे मध्यवर्गीय समुदाय की तटस्थ भूमिका बढ़ जाती है जो बहुत ही अधिक विकसित वर्गीय होने वाले देशों के इसी प्रकार के समुदाय की अपेक्षा वर्गों के प्रगम में तुलनात्मक रूप में अधिक स्वतन्त्र होती है।

सामान्यता इन देशों के अफसरों का समूह जमींदारों और बड़े पूँजीपति-वर्ग से बहुत कम सम्बन्धित होता है। अफसर मुख्यतः शहरी तथा ग्रामीण निम्न पूँजीवादी परिवारों, अर्थात् उस सामाजिक थैली से आते हैं। इसी कारण देशभक्त अफसर केवल साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के ही विरुद्ध नहीं बल्कि पूँजीवाद के विरुद्ध भी होते हैं।

2. विकसित समाज के प्रतिकूल जहाँ सेना सर्वाधिक निश्चेष्ट तथा निष्क्रिय भग है, औद्योगिक दृष्टि से अधिकतम देशों में वह सर्वाधिक प्रबुद्ध तथा गतिशील शक्ति होती है। इसका कारण यह है कि सेना को युद्ध सम्बन्धी आधुनिक सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है। जिसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके अफसरों को दूसरे देशों की यात्रा करनी पड़ती है और उन्नत देशों के अफसरों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। वे स्वभावतः देश के आर्थिक तथा तकनीकी पिछड़ेपन से होने वाली क्षतियों की अन्य समूहों से बहुत पहले महसूस करने लगते हैं।

अफसरों का उत्पादन के आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त करने का मतलब है प्रगतिशील विचारों का ज्ञान प्राप्त करना, और जब वे स्वदेश वापस लौटते हैं तो चाहे नए समाज के निर्माण के लिए उनके पास कोई निश्चित कार्यक्रम न हो, फिर भी वे राजनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता के प्रति बहुत ही जागरूक हो जाते हैं।

3. सेना राष्ट्रीय मुक्ति के लिए जनता के सघर्ष से पृथक् नहीं रहती और प्रारम्भिक अवस्था में ही स्वतन्त्रता के विचारों से प्रभावित हो जाती है। अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के विकास के साथ ही राष्ट्रीय सेनाओं का गठन हुआ और इस कारण वे शुरू से ही प्रगतिशील एवं साम्राज्यवाद विरोधी शक्ति रहे हैं। अल्जीरिया के सम्बन्ध में यही बात थी जहाँ उपनिवेशवाद-विरोधी युद्ध में लड़ते तथा सम्पूर्ण अल्जीरियाई जनता के हितों और आकांक्षों को

प्रकट करने वाले किसानों, मजदूरों तथा निम्न पूँजीपति वर्गों के सदस्यों को शामिल कर राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन हुआ था। जापानी आक्रमणकारियों, और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को देश से मार भगाने वाली बर्मी स्वातन्त्र्य सेना के मुख्य भाग का गठन भी किसानों, मजदूरों और शहरों के गरीब लोगों को शामिल करके किया गया था।

4 राष्ट्रीय मुक्ति मधव काल में और अधिकतर राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के बाद अनेक स्वाधीन देशों में जो राजनीतिक पार्टियाँ अस्तित्व में आईं, वे अपने गठन की दृष्टि से इतनी अविकसित थी कि अपने देशों के विकास का दायित्व ग्रहण नहीं कर सकती थी। सम्भवतः भारत को छोड़कर प्रायः किसी भी नवोदित देश में शासन करने में सक्षम पूँजीवादी पार्टियाँ नहीं थी। जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टियों का सम्बन्ध है अधिकांश देशों में या तो उनका अस्तित्व ही नहीं था अथवा भीषण दमन का शिकार होने के कारण वे छिपकर काम करने को विवश थीं और इसलिए घटनाक्रम पर पर्याप्त रूप से सक्रिय प्रभाव नहीं डाल सकती थी।

कई देशों में जो पार्टियाँ सत्तारूढ़ हुईं उन्हें वास्तव में सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक दृष्टियों में विभिन्न शक्तियों को एकजुट करने वाले और मार्क्स-भोम राष्ट्रो के सम्मुख प्रस्तुत प्रतिजटिल कार्यभारों को पूरा करने के लिए अल्प तैयारी वाले राष्ट्रीय मोर्चे के ढंग के संगठनों के रूप में ही समझा जा सकता था।

ऊपर जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनसे कुछ हद तक यह स्पष्ट हो जाता है कि तीसरी दुनिया के कई देशों में राजनीतिक घटनाक्रम के फलस्वरूप सेना समाज की एक बहुत ही संगठित शक्ति के रूप में किस प्रकार आगे आई।

किन्तु व्यवहार और सिद्धान्त में भी दरा तथ्य की उपेक्षा करना गमत होगा कि राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के विकास में जब सामाजिक आर्थिक समस्याएँ प्राथमिकता ग्रहण करती हैं और नवोदित स्वाधीन देशों के लिए अर्थतन्त्र के अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जाने से समाज में सेना के कार्य और स्थिति में भी काफी परिवर्तन हो जाते हैं तो सेना की सहायता से सत्तारूढ़ हुए सैनिक नेता यह महसूस करने लगते हैं कि सेना जिसके सारे कार्य आदेशों तथा हिदायतों द्वारा होते हैं, समाज की जनवादी समस्याओं का स्थान ग्रहण कर सकती है और इसके बिना कोई भी राष्ट्रीय क्रान्ति अच्छी प्रगति नहीं कर सकती।

वास्तविकता का सामना करते हुए इनमें से कई सैनिक नेताओं को अधिवाधिक रूप में यह पक्का विश्वास हो गया कि एक निश्चित राजनीति तथा सैद्धान्तिक कार्यक्रम से रहित और जनता में सामाजिक की पथ-प्रदर्शनकारी शक्ति के रूप में एक पार्टी का स्थान नहीं कर सकती।

सेना को अपने विनिष्ट कार्यभार, मुख्यतः विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों और घरेलू प्रतिनिध्यावादियों के हस्तक्षेप से क्रान्तिकारी उपलब्धियों की रक्षा का काम पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक और सैद्धान्तिक एकात्मता से रहित सेना राष्ट्रीय विकास के पथ का चयन करने का प्रश्न होने ही स्वयं को दो विरोधी

है और उनके निवासी ऐतिहासिक परिस्थिति का शिकार होने के बदले स्वयं अपने भविष्य के जागरूक निर्माणकर्ता बने हैं। एशिया में भारी राजनीतिक हार खाने के बाद औपनिवेशिक शक्तियों ने अफ्रीका में दृढ़ता से टिके रहने की आशा की, परन्तु अफ्रीका भी बहुत समय तक निश्चेष्ट नहीं रहा। सबसे पहले उत्तरी और उसके बाद उपएकदिवन्धीय अफ्रीका में उपनिवेशवाद की आधारशिला को ध्वस्त करती हुई साम्राज्यवाद-विरोधी क्रान्तियाँ उत्तरोत्तर जोर पकड़ने लगीं। आज, कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सारा एशिया और अफ्रीका साम्राज्यवाद से मुक्त हो चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सक्रिय साम्राज्यवाद-विरोधी शक्ति के रूप में सर्वसत्ता सम्पन्न राज्यों का उदय राष्ट्रीय मुक्ति-प्रान्दोलन का एक बहुत महत्त्वपूर्ण परिणाम तथा गुलाम और पराधीन देशों के लोगों के लम्बे और कठोर संघर्ष की तर्कसंगत परिणति है। सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के सदस्य यू. ज़ुकोव तथा अन्य लेखकों द्वारा सम्पादित पुस्तक 'तीसरी दुनिया' में, प्रो. इस्केंदरोव ने अपने लेख 'वर्तमान युग और राष्ट्रीय मुक्ति प्रान्दोलन' में आधुनिक युगीन राष्ट्रीय मुक्ति-प्रान्दोलनों की सफलता के कारणों तथा इसके नवीन पहलुओं का बड़ा तार्किक और विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है।

राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की सफलता के कारण¹

1. सबसे मुख्य और निर्णायक कारक सन् 1917 की रूसी समाजवादी क्रान्ति थी, जिसने लाखों-करोड़ों लोगों की प्रमुख शक्ति को जगाया और उन्हें राजनीतिक मामलों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। रूस की क्रान्तिकारी घटनाओं के फलस्वरूप औपनिवेशिक जगत् में परिवर्तन आने लगे, पूँजीवादी दुनिया का विघटन शुरू हुआ, पूँजीवाद का आम संकट उभरने लगा और साथ ही साम्राज्यवादी औपनिवेशिक प्रणाली भी संकट में पड़ गई। सन् 1917 से पहले अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी शक्ति ने, जिसका उस समय सारी दुनिया पर एकछत्र शासन था, उपनिवेशों और अर्द्ध-उपनिवेशों के सभी राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्षों को कुचल दिया था। अक्तूबर क्रान्ति से इस स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया। यह राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष के विकास में युगान्तरकारी परिवर्तन का चेतक था। इसके बाद उपनिवेशों तथा गुलाम देशों में बहुत बड़े पैमाने पर क्रान्तिकारी प्रान्दोलन विकसित हुआ और संगठनात्मक रूप में उसमें सुधार हुआ। अक्तूबर क्रान्ति ने अन्य देशों के क्रान्तिकारियों के मन में अपनी मुक्ति के लिए विश्वास की भावना पैदा कर दी।

2. नाजी जर्मनी और साम्यवादी जापान की सामरिक पराजय तथा यूरोप और एशिया के कई देशों में विजयी समाजवादी क्रान्तियों से साम्राज्यवाद और उसकी औपनिवेशिक प्रणाली को गहरी चोट पहुँची। पहले से ही संकटग्रस्त यह प्रणाली खण्ड-खण्ड होने लगी।

3. समाजवाद के एक देशीय सीमा के बाहर भी फैल जाने और विश्व-समाजवादी प्रणाली के गठन से अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-सन्तुलन में आमूल परिवर्तन आया

और राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन के सफल विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पदा हुईं। यदि समाजवादी व्यवस्था सारी दुनिया के विकास पर उत्तरोत्तर अधिक प्रभाव डालने वाली महान् शक्ति न हो गयी होती तो साम्राज्यवादी औपनिवेशिक प्रणाली के द्रुत विघटन जैसी महत्वपूर्ण घटना कभी न घटी होती, जिसके फलस्वरूप 1 अरब 50 करोड़ से अधिक लोग स्वतन्त्र हो चुके हैं।

4 अब समाजवाद नहीं बल्कि, विश्व-समाजवादी प्रणाली और समाज के समाजवादी नव-निर्माण के हित साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वाली ताकते मानव-जाति के ऐतिहासिक विकास के मुख्य अन्तर्ग, मुख्य रुझान और मुख्य सक्षमों को निर्धारित करती हैं। अपनी बढ़ती हुई आन्तरिक असमग्रियों से पूर्ण पूँजीवादी प्रणाली गम्भीर संकट के दौर से गुजर रही है। निस्सन्देह एक प्रणाली के रूप में पूँजीवाद के बारे में ऐसी धारणा बिल्कुल गलत होगी कि वह आन्तरिक असमग्रियों के ग्रस्त होने के कारण स्वतः-ध्वस्त हो जाएगी। युद्धोत्तर-काल के अनुभावों से सिद्ध होता है कि पूँजीवाद अपने लाभ के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की उपनधिधियों, उत्पादन के स्वचालितकरण, राजकीय नियन्त्रण के नए रूपों और तरीकों, आर्थिक एकीकरण, अर्थ-व्यवस्था के संयोजन और अन्य अनेक कारकों का उपयोग करने में सफल रहा है। किन्तु इससे पूँजीवाद की बुनियादी कूटियाँ दूर नहीं हुई हैं और न कभी हो सकती हैं। सभी प्रयासों के बावजूद पूँजीवाद प्रणाली अपनी गतिहीनता को दूर करने में विफल रही है। दूसरी तरफ, पूँजीवाद से अपनी आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता में विश्व-समाजवाद निरन्तर सफलताएँ प्राप्त कर रहा है। यह चाहे-अनचाहे पूँजीवाद अर्थशास्त्रियों को भी स्वीकार करना पड़ता है।

आधुनिक पूँजीवाद के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे पूँजीवादी समाज की बुनियादी आन्तरिक असमग्रि अर्थात् श्रम और पूँजी के बीच का विरोध दूर नहीं हुआ है। वास्तविकता तो यह कि वर्गगत शक्तियों का मतभेद बढ़ते जाने से यह असमग्रि और अधिक तीव्र हो गई है। युद्धोत्तर-काल में विकसित पूँजीवाद देशों में हड़ताल-आन्दोलन का और विस्तार हुआ है। सन् 1919-1939 के बीच 1,65,600 हड़तालें हुईं जिनमें 7,45,00,000 मजदूरों ने भाग लिया जबकि सन् 1946 से 1966 के बीच हड़तालों की संख्या 3,09,800 और उनमें भाग लेने वाले मजदूरों की संख्या 25,91,00,000 हो गई थी। इस तरह युद्ध-पूर्व काल की तुलना में हड़तालियों की औसत वार्षिक संख्या 3.5 गुना अधिक हो गई है।

5. आजकाल मजदूर-वर्ग का संघर्ष दिनोदिन उपनिवेशवाद-विरोधी स्वरूप धारण करता जा रहा है। मजदूर वर्ग साम्राज्यवादी आक्रमण के शिकार राष्ट्रों की रक्षा में अधिकाधिक सामने आता जा रहा है। युद्धोत्तरकाल में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-आन्दोलन के विकास का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, संयुक्तराज्य अमरीका, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन और पुर्तगाल की प्रगतिशील शक्तियों ने पराधीन तथा अर्द्ध-पराधीन राष्ट्रों की मुक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

6. एशिया और अफ्रीका की राष्ट्रीय मुक्ति-प्रगतिशील घनिष्ठ आपसी सम्पर्क और सहयोग की परिस्थितियों में विकसित होती हैं, उनमें अलग-अलग रूप से विकास

करने की प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष करने वाला कोई भी राष्ट्र जब स्वतन्त्र राज्यत्व प्राप्त करता है तो अपनी आजादी और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्षरत पराधीन राष्ट्रों को भी इससे वास्तविक लाभ पहुँचता है। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपनी एकता और भाई-चारे की भावना का अमोघ हथियार ढाल लिया है। जिन राष्ट्रों ने आजादी प्राप्त करली है अथवा प्राप्त करने वाले हैं, उनके घ्येय एक समान हैं और साम्राज्यवाद उनका समान शत्रु है। ठीक यही बात उनके सक्रिय, जुझारू संघर्ष का वस्तुगत आधार है, हालाँकि उनके संघर्ष की पद्धतियों में भेद हो सकता है जो उसमें भाग लेने वाले वर्गों अथवा सामाजिक श्रेणियों के स्वभावगत अन्तर और विचार पद्धति, राजनीतिक धारणाओं एवं धार्मिक विश्वास में भिन्नता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।

7. एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति-क्रान्तियों के सफल विकास के विदेश-नीति सम्बन्धी यही बुनियादी कारक हैं। परन्तु यदि खुद उपनिवेशों और पराधीन देशों में आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार तैयार न होता तो क्रान्तियाँ जिस रूप में सफल हुई हैं, उस रूप में सफल न हो पाती। इसी प्रकार विजय का एक कारक उन सामाजिक शक्तियों का प्रादुर्भाव रहा है जो राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के अलावा उसका नेतृत्व करने में भी सक्षम सिद्ध हुई है।

8. राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने के ठीक पूर्ववर्ती वर्षों में सभी सामाजिक श्रेणियों ने द्रुतगति से बढ़ती हुई राजनीतिक विवाशीलता का परिचय दिया। प्रायः सर्वत्र मजदूरों और किसानों ने महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ की। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही ट्रेड-यूनियनों और विविध आम जनवादी संगठन अस्तित्व में आ गए। उदाहरणार्थ, सन् 1946 के अन्त और 1947 के शुरु में भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में उद्योग की प्रायः सभी शाखाओं के मजदूर, किसान, बैंक-कर्मचारी, शिक्षक आदि शामिल हुए। स्वतन्त्रता की माँग अब आम माँग हो गई, मजदूरों से लेकर राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग सहित सभी वर्गों तथा सभी प्रगतिशील पार्टियों और संगठनों ने इसका समर्थन किया। सन् 1946-47 में बर्मा में किसानों मजदूरों, नौकरोंपेशा लोगों और विद्यार्थियों ने सच्ची स्वतन्त्रता की माँग के समर्थन में सारे देश में अनेक सभाएँ, प्रदर्शन और हड़ताले की। सन् 1947 की जनवरी में बर्मा की स्थिति आम राजनीतिक हड़ताल के बिल्कुल निकट थी।

9. पराधीन अफ्रीका में भी आजादी की सभी श्रेणियाँ अधिकधिक रूप में सक्रिय हो गई थीं। उष्णकटिबन्धीय अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन के विकास के साथ-साथ ट्रेड-यूनियनों तथा राजनीतिक पार्टियाँ संगठित की गईं जिन्होंने विभिन्न सामाजिक वर्गीय शक्तियों को एकजुट किया और जो राजनीतिक स्वाधीनता के लिए उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करने वाले कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय जनवादी मोर्चे के ढंग के संगठन थे।

10 उसी काल में सभी देशभक्त शक्तियों और राजनीतिक पार्टियों का संश्रय अस्तित्व में आया और राष्ट्रीय मुक्ति-क्रान्तियों की अपेक्षाकृत द्रुत विजय का यह एक मुख्य कारण था। आज भी यह संश्रय भूतपूर्व उत्पीड़ित राष्ट्रों के हाथों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हथियार है क्योंकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय मुक्ति-क्रान्तियों के नए पहलू

वर्तमानकाल में राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन की कुछ नई विशेषताएँ प्रकाश में आई हैं जिनसे 19वीं सदी के अन्त और 20वीं सदी के प्रारम्भ की पूँजीवादी-जनवादी क्रान्तियों से इसकी भिन्नता प्रकट होती है—

1. वर्तमान समय में जितने अधिक देश और लोग राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन में शामिल हैं उतने पहले कभी शामिल नहीं थे। अब यह एक ही देश तक सीमित नहीं है, इसमें दुनिया की कुल आबादी का तीसरा भाग शामिल है और यह कहा जा सकता है कि इसने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। अब केवल किसी एक औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध लड़ित न होने के कारण, यह सम्पूर्ण साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के लिए चुनौती बन गया है।

पूँजीवाद के आम संकट की एक अभिव्यक्ति के रूप में दुनिया के व्यापक क्षेत्रों में न्यूनाधिक एक साथ ही पैदा होकर अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का यह राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन अपने में जिन राष्ट्रीय शक्तियों को शामिल करता है, उनके विकास के स्तर भिन्न-भिन्न होते हैं। यह इस आन्दोलन में सम्मिलित देशों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं तथा भिन्न-भिन्न देशों में इस आन्दोलन के स्वरूप, इगमें सम्मिलित होने वालों के वर्गीय ढाँचे और इसके नेताओं की कुशलता का परिणाम है।

2. वर्तमान राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन के फलस्वरूप नए सार्वभौम राज्यों की एक शृंखला अस्तित्व में आ गई है, जिन्होंने विश्व-पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था से अपना सम्बन्ध तो पूर्णतया समाप्त नहीं किया है, परन्तु अधिकांशतः अब साम्राज्यवादी राजनीतिक प्रणाली के अंग भी नहीं हैं। अनेक स्वाधीन एशियायी और अफ्रीकी राज्य सक्रिय साम्राज्यवाद-विरोधी नीतियों का अनुसरण करते हैं और मानवजाति के हितों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के निराकरण में भाग लेते हैं। वे आक्रमण और युद्ध की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करने में समाजवादी देशों का साथ देते हैं और राष्ट्रों के बीच शान्ति तथा दोस्ती को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान करते हैं।

साम्राज्यवादी शक्तियाँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नवोदित स्वाधीन राज्यों के बढ़ते हुए प्रभाव और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रगतिशील परिवर्तनों से भयभीत हैं। वे विकसित देशों की विदेश-नीतियों में किसी भी तरह की जनवादी प्रवृत्ति को भेजना चाहेगी, और उनकी यही इच्छा होगी कि ये देश उनकी साम्राज्य नीति का अनुसरण करें।

विविधों में विभक्त पाएंगी क्योंकि राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद वर्ग-विभेद की तीव्र प्रक्रिया से वह मुक्त नहीं होगी।

इन परिस्थितियों में जन-समुदाय की मनोभावना को प्रकट करने वाले तथा जन-समर्थन प्राप्त देशभक्त अफसरों का समूह निस्संकोच मुक्ति-क्रान्ति को अग्रसर करने और अपने देश के सामाजिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए भूलभूत सामाजिक-आर्थिक सुधारों को लागू करने का निर्णय करेगा, किन्तु साम्राज्यवादियों और घरेलू प्रतिक्रियावादियों से प्रभावित अफसर या तो 'प्रतीक्षा करो और देखो' की नीति अपनाएँगे अथवा खुले रूप में क्रान्ति को चुनौती देंगे। कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के सैनिक विद्रोहों के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि सेना राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन में न केवल प्रगतिशील भूमिका अदा कर सकती है बल्कि जनवादी विचारों का प्रभाव कम होने पर वह आसानी से प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथों का खिलौना भी बन सकती है।

कुछ अवस्थाओं में सेना नवीरहित स्वाधीन राज्य के प्रगतिशील विकास की तीव्रता प्रदान करती है, कुछ दूसरी अवस्थाओं में वह इस प्रकार के विकास में अवरोध पैदा कर सकती है। समाज के ढाँचे के अन्तर्गत सेना एक ऐसी सत्ता है जिसमें जनवादी दृष्टिकोणों के साथ-साथ प्रतिक्रियावादी विचार भी विद्यमान रहते हैं, जिसके फलस्वरूप यह खतरा पैदा होता है कि इन विचारों के कुछ पक्षधर क्रान्ति के खिलाफ अथवा उसके एक पक्ष का इस्तेमाल करेंगे। सेना के भीतर छिपी इन प्रवृत्तियों (जनवादी अथवा प्रतिक्रियावादी) में से विशेष ऐतिहासिक अवस्था में यौन-सी हाकी होगी, यह अनेक कारणों किन्तु सर्वोपरि रूप से देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के दायरे और तीव्रता पर निर्भर करती है जो सेना में मानसिक हलचल पैदा कर सपत्ता है तथा सारी सेना या उसके काफी बड़े भाग को क्रान्ति के पक्ष में कर लेने में समर्थ होता है।

कभी सैनिक विद्रोह के नेता सत्ता हथियाने की विमृष्ट पदलोलुपता की अपेक्षा राजनीतिक विचारों से कम प्रेरित होते हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि साम्राज्यवादी अपने उपनिवेशवादी हितों में इन प्रवृत्तियों का उपयोग करने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ सेना में उनके विकास को देखते रहते हैं।

कुछ अफ्रीकी देशों के सैनिक विद्रोहों तथा अफ्रीका में साम्राज्यवादी राष्ट्रों की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के बीच इस तथ्य को देखना असम्भव नहीं है। साम्राज्यवादी बड़ी कुशलता के साथ इस बात का लाभ उठा रहे हैं कि उपनिवेशवादियों के हट जाने के बाद अनेक अफ्रीकी देशों की सेनाओं के स्वरूप और ढाँचे में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। अधिकांश देशों की सेनाएँ भाड़े की होती हैं और उनका प्रशिक्षण पश्चिमी 'प्रशिक्षकों' के सुपुर्द कर दिया गया है।

राष्ट्रीय क्रान्ति के लिए सेना में राजनीतिक प्रचार के महत्त्व को कम आँकने प्रयत्न इसे राजनीति से वृथक् शक्ति के रूप में समझने के परिणाम सेवजनक हो सकते हैं।

युद्ध (War)

युद्ध का इतिहास मानव-जाति का इतिहास रहा है। राजनीतिक संस्थाओं, विशेषकर राज्य के विकास में शक्ति अथवा युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सम्यता के विकास के साथ-साथ युद्ध की भयानकता बढ़ती गई है। आज के परमाणु-युग में कोई महायुद्ध कितना भयानक हो सकता है—इसकी कल्पना भी कठिन है। प्रायः यही स्वीकार किया जाता है कि कोई भी तृतीय विश्व-युद्ध, जिसमें अणु-प्रायुधों का खुलकर प्रयोग किया जाएगा, मानव-सम्यता को ध्वस्त कर देगा। विजित और विजेता की स्थिति समान होगी। युद्ध के इसी भय की दृष्टि से निःशस्त्रीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि अभी तक जो सफलता मिली है वह ऊँट के मुँह में जीरे के समान है।

युद्ध का अर्थ (Mean ng of War)

युद्ध क्या है ? इसका क्या तात्पर्य है ? आदि के सम्बन्ध में विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। क्विंसी राइट के अनुसार युद्ध व्यापक अर्थ में—“स्पष्टतः भिन्न किन्तु एक ही इकाइयों के बीच हिंसापूर्ण सम्पर्क है।” युद्ध के सीमित और संकीर्ण अर्थ को स्पष्ट करते हुए क्विंसी राइट ने लिखा है कि इसका अभिप्राय “उस कानूनी स्थिति से है जो दो या उससे भी अधिक विरोधी समुदायों को सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से संघर्ष के संचालन की समान रूप से अनुमति प्रदान करती है।”

प्रो मेलिनोस्की (Professor Malinowski) के मतानुसार युद्ध स्वतन्त्र राजनीतिक इकाइयों के बीच का सशस्त्र संघर्ष है। यह राष्ट्रीय अथवा जातीय नीतियों की साधना के लिए संगठित सैनिक शक्तियों द्वारा किया जाता है। मेलिनोस्की की इस परिभाषा को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- (1) युद्ध करने वाली इकाइयाँ राजनीतिक रूप से स्वतन्त्र होती हैं।
- (2) युद्ध एक सशस्त्र संघर्ष है जो संगठित सैनिक शक्तियों द्वारा किया जाता है।
- (3) युद्ध जातीय (Tribal) अथवा राष्ट्रीय नीतियों की साधना के लिए किया जाता है।

युद्ध की इस परिभाषा में युद्ध की जो विशेषताएँ बताई गई हैं वे प्रायः एक साथ संयुक्त रूप में प्रत्येक युद्ध में प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए गृह-युद्ध होते हैं तो उनके वर्त्ता दो स्वतन्त्र राजनीतिक इकाइयाँ नहीं होतीं। इसी प्रकार वर्तमान काल में आर्थिक युद्ध, शीत-युद्ध, राजनीतिक-युद्ध आदि में संगठित सशस्त्र सेनाओं का सहारा नहीं लिया जाता। सन् 1965 का भारत-पाक-संघर्ष संगठित सशस्त्र सेनाओं द्वारा राष्ट्रीय नीति की साधना के लिए किया गया दो स्वतन्त्र राजनीतिक इकाइयों के बीच का संघर्ष था, किन्तु ऐसा होते हुए भी उसको तकनीकी अर्थों में युद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध बने हुए थे तथा किसी भी पक्ष द्वारा सरकारी तौर पर युद्ध की घोषणा की गई थी।

नवीन अंग्रेजी शब्दकोष द्वारा की गई परिभाषा गृह-युद्ध को भी अपने में समाहित कर लेती है। उसके अनुसार युद्ध सशस्त्र शक्ति द्वारा शत्रुतापूर्ण व्यवहार है जो कि राष्ट्रों, राज्यों या शासकों के बीच होता है या एक ही देश के दलों के बीच होता है। यह विदेशी शक्ति के विरुद्ध या उसी राज्य के विरोधी दल के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग है। युद्ध के सामान्य स्वरूप को चित्रित करने वाली एक दूसरी परिभाषा सरल शब्दों में हॉफमैन निकर्सन (Hoffman Nickerson) द्वारा की गई है। वे कहते हैं कि युद्ध दो ऐसे मानव-समूहों के बीच किया जाने वाला व्यवस्थित दल प्रयोग है जो विरोधी नीतियों का अनुसरण करते हैं तथा जिनमें से प्रत्येक अपनी नीति को दूसरे पर लागू करने का प्रयत्न करता है। युद्ध के एक जर्मन विचारक कार्ल क्लाजविच (Karl Clausewitz) का कहना है कि 'युद्ध' राजनीतिक व्यवहार का आवश्यक अंग है और इसलिए अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है। युद्ध और कुछ नहीं केवल कुछ अन्य साधनों के साथ राजनीतिक व्यवहार (Political intercourse) है। गामर तथा पकिंस के कथनानुसार क्लाजविच की उपयुक्त नहीं है; फिर भी यह सच है कि इसके द्वारा युद्ध के स्वरूप की एक भूलक का आभास मिलता है। 'न शान्ति न युद्ध' की जो स्थिति वर्तमान है उसका इसके द्वारा दिग्दर्शन कराया गया है।

युद्ध की जो परिभाषाएँ दी गई हैं, वे पूर्णतः उपयुक्त नहीं हैं तथा उनके आधार पर युद्ध के सभी रूपों का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता तथापि इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर युद्ध के निम्नलिखित मुख्य तत्त्व उजागर होते हैं—

1. युद्ध के लिए एक से अधिक समूहों की आवश्यकता होती है। इन समूहों के मूल उद्देश्य परस्पर विरोधी होते हैं।
2. इन समूहों के हित परस्पर इतने विरोधी और उग्र हो जाते हैं कि सम्झौते की सम्भावना प्रायः नहीं रहती। यदि सम्भावना होती भी है तो भी दोनों पक्ष या कोई एक पक्ष सशस्त्र सन्धियों की ही ढान लेता है। भारत-पाक युद्ध के सन्दर्भ में यह स्थिति हमारे समक्ष स्वतः स्पष्ट है।
3. अपने हितों की प्राप्ति के लिए शक्ति का कई प्रकार से व्यवस्थिति प्रयोग किया जाता है।
4. युद्ध का उद्देश्य अपने हितों को प्राप्त करना और दूसरे पक्ष पर अपनी इच्छा को थोपना होता है।

सबसे प्रमुख बात यह है कि युद्ध के माध्यम से कोई राष्ट्र अपने हित की अभिवृद्धि का ही आकांक्षी होता है। यदि किसी देश को युद्ध से किंचित् लाभ भी लाभ की आशा दिखाई न देती हो तो वह इतनी भारी राष्ट्रीय जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी यह भी होता है कि राष्ट्र युद्ध न चाहते हुए भी युद्ध से फँस जाता है। यह भी होता है कि युद्धोन्माद में राष्ट्र अपने हानि-लाभ को सोचने का सन्तुलन खो बैठता है और युद्ध छेड़ देता है। भारत पर

पाकिस्तान का आक्रमण इस मनोदशा का ज्वलन्त उदाहरण है। सामान्यतः युद्ध केवल आवश्यक हितों की प्राप्ति के लिए ही अपनाया जाता है, साधारण हित तो समझौते द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

सन् 1945 से 1972 तक अट्ठावन युद्ध
(Fifty Eight Wars since 1945)

मानव-इतिहास के पृष्ठ छोटे-मोटे सहस्रो युद्धों से भरे पड़े हैं। रोजन एवं जोन्स ने सन् 1945 से लेकर 1972 तक विश्व में हुए 58 युद्धों की सूची प्रस्तुत की है जो इस बात की परिचायक है कि—(i) युद्धों को रोकने के अनवरत प्रयासों के बावजूद युद्ध होते रहे हैं और इस प्रकार युद्धों की 'अनिवार्यता' प्रकट होती है, (ii) संयुक्तराष्ट्र संघ के रूप में विश्व-शान्ति की स्थापना का जो शक्तिशाली यन्त्र है वह भी युद्धों पर कोई प्रभावी रोक नहीं लगा सका है। कुछ गम्भीर युद्धों को महायुद्धों में परिणत होने से रोकने में उसकी भूमिका अवश्य प्रशंसनीय रही है, विशेषकर इसीलिए कि उन अवसरों पर इस समस्या को महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त था, (iii) आज का युग 'आणविक' युग है और कोई भी छोटा-सा तथा स्थानीय युद्ध भी महायुद्ध के लिए 'विस्फोटक' बन सकता है अतः विश्व के राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों को तथा विश्व की सरकारों को निःशस्त्रीकरण की दिशा में ईमानदारी से प्रयत्न करने चाहिए। रोजन एवं जोन्स की सूची इस प्रकार है—

सन् 1945 से 1972 तक अट्ठावन युद्ध¹
(Fifty Eight Wars since 1945)

युद्ध	आरम्भ	पूरा	आरम्भ
सीरिया लेबनान	1945	कांगो	1960
इण्डोनेशिया	1945	कोलम्बिया	1960
चीन	1945	बर्मा (बिर्मा की लड़ाई)	1961
मलाया	1945	गोआ	1961
इण्डोचीन	1946	अंगोला	1961
यूनान	1946	घबन	1962
मेडागास्कर	1947	पश्चिमी न्यू गायना	1962
भारत-पाकिस्तान	1947	पुर्तगाली गायना	1962
काश्मीर	1947	अल्जीरिया मोरक्को	1963
फिलिपाइन्स	1948	साइप्रस	1963
इजरायल	1948	मलेसिया	1963
हैदराबाद	1948	सोमालिया-केन्या	1963
बर्मा	1948	बर्माकार	1964
कोरिया	1950	साईलैण्ड	1964

युद्ध	कारण	युद्ध	कारण
फारसूना	1950	मोजाम्बिक	1964
तिब्बत	1950	बोमिनिकन गणराज्य	1965
केनिया	1952	भारत पाकिस्तान	1965
आटेमाता	1954	इण्डोनेशिया	1965
अल्जेरिया	1954	विवाका	1966
सूडान	1955	इजरायल	1967
साइप्रस	1955	चेकोस्लोवाकिया	1968
सिनाई	1956	मलेशिया	1969
हंगरी	1956	अल्बानिया	1969
स्वेज	1956	छाद	1969
सेयना	1958	उत्तरी आयरलैंड	1969
बयूना	1958	इथियोपिया (दरीदिया)	1970
बियतनाम	1959	आटेमाता	1970
हिमालय	1959	बंगलादेश/काश्मीर	1971
इराक	1959	दक्षिणी	1972
लाओस	1959		

इन युद्धों के बाद कुछ और भी युद्ध हो चुके हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अक्टूबर, 1973 का अरब-इजरायल युद्ध था। सन् 1975 में बियतनाम युद्ध का भी पुनः गम्भीर रूप से विस्फोट हो गया था।

युद्ध के बारह कारण (Twelve Causes of War)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है—युद्ध के कारण। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विवाद आखिर क्यों हिंसात्मक बन जाते हैं? अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास के पृष्ठ खून से रंगे हुए हैं और एक नैतिकतावादी यह प्रश्न कर सकता है कि लोग युद्ध में उस व्यवहार को क्यों क्षमा कर देते हैं जिस व्यवहार को वे शान्ति-काल में सहन करने को तैयार नहीं होते। क्या युद्ध मानवीय सामाजिक व्यवस्था में एक अन्तर्राष्ट्रीय रोग है, एक सामूहिक पागलपन अथवा उन्माद है, सीडियो से गिर पड़ने जैसा एक दुष्कृत्य है? क्या यह कतिपय हितों और गुटों के पड़पड़ की उपज है अथवा युद्ध, भयानक होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक विवेकपूर्ण और प्रकाशपूर्ण अंग है? ¹

विभिन्न विचारकों ने युद्ध के मूल और गौण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों का विवेचन किया है। युद्ध के कारणों को प्रायः दो भागों में बाँटा गया है—प्रथम भाग में उन तात्कालिक कारणों को सम्मिलित किया गया है जो युद्ध की आग भड़का देते हैं, दूसरे भाग में उन शेष कारणों को लिया जाता है जो युद्ध के लिए एक लम्बे समय से ही अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे थे। प्रथम महायुद्ध के कारणों का

1 Steven J. Rosen & Walter S. Jones : The Logic of International Relations, 1974, p. 231

अध्ययन करते हुए प्रो. सिडनी बी. फे (Sidney B. Fay) ने बताया है कि युद्ध का सबसे मूल कारण गुप्त सन्धियों की व्यवस्था (System of Secret Alliances) थी जो फ्रैंको-प्रशियन युद्ध के बाद प्रारम्भ हुई थी। दूसरे अन्य सहायक कारण चार थे—सैनिकवाद, राष्ट्रवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद और समाचार-पत्र प्रकाशन। क्विंसी राइट (Quincy Wright) ने युद्ध के विभिन्न कारणों का वर्णन किया है जिनमें कुछ तो मूल हैं और कुछ तात्कालिक। कभी-कभी कुछ घटनाएँ युद्ध का कारण बन जाती हैं, कभी लोगों की मनोभावनाएँ एवं महत्वाकांक्षाएँ युद्ध को उकसाती हैं। इनके अतिरिक्त शस्त्रों की दौड़, बूटनीतिक व्यवहारों की अकुशलता, वाणिज्य-नीतियाँ, सम्प्रभुता की मान्यता, उपनिवेशों के मतभेद, देश के विस्तार की प्रवृत्ति, आदि अन्य बातें भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध को भड़काने में सहायक होनी हैं। क्विंसी राइट के मतानुसार युद्ध के कारणों को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। इसके राजनीतिक, तकनीकी, सैद्धान्तिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक कारण हैं। टर्नर (T. A. Turner) ने अपनी पुस्तक 'युद्ध के कारण और नवीन क्रान्ति' (The Causes of War and the New Revolution) में युद्ध के 41 कारणों का उल्लेख किया है। वे इन कारणों को चार भागों में विभाजित करते हैं—आर्थिक, राजवश सम्बन्धी, धार्मिक और भावात्मक। अन्य अनेक विचारकों द्वारा भी युद्ध के कारणों की व्यवस्था की गई है।

स्टीवेन जे. रोजन तथा वाल्टर एस जोन्स ने अपनी 1974 में प्रकाशित पुस्तक 'The Logic of International Relations' में बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक रूप में युद्ध के बारह कारणों को प्रस्तुत किया है और इन्हें 'युद्ध के कारणों के बारह सिद्धान्तों' (Twelve Theories of the Causes of War) का नाम दिया है। ये बारह सिद्धान्त हैं—

- (1) शक्ति-विषमता (Power Asymmetries)
- (2) राष्ट्रवाद, पृथक्तावाद और भूमि-अपहरणवाद (Nationalism, Separatism and Irredentism)
- (3) अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक डार्विनवाद (International Social Darwinism)
- (4) संचार-असफलता और पारस्परिक सन्देशबोध (Communications' Failure and Mutual Misperception)
- (5) अनियन्त्रित शस्त्रास्त्र दौड़ (Runaway and Uncontrolled Arms Races)
- (6) बाह्य संघर्ष के माध्यम से आन्तरिक एकीकरण की अभिवृद्धि (The Promotion of Internal Integration through External Conflict)
- (7) स्वतः प्रेरित आक्रमण, हिंसा के प्रति मौखिक रमान और युद्ध-शान्ति के चक्र (Instinctual Aggression, Cultural Propensities to Violence, and War Peace Cycles)

- (8) आर्थिक और वैज्ञानिक उत्तेजनाएँ (Economic and Scientific Stimulation)
- (9) सैनिक-औद्योगिक समूह (The Military-Industrial Complexes)
- (10) सापेक्ष बंचन या हरण (Relative Deprivation)
- (11) जनसंख्या की सीमा (Population Limitation)
- (12) संघर्ष संकल्प (Conflict Resolution)

1. शक्ति-विषमता (Power Asymmetries)—युद्ध का एक प्रमुख कारण शक्ति-विषमता है अर्थात् शक्ति के वितरण में एक प्रतिकूल झुकाव (An unfavourable tilt in the distribution of power) होने से युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है। विरोधियों में जब शक्ति का सावधानीपूर्ण सन्तुलन बना रहता है तो युद्ध पर रोक लगने की प्रवृत्ति पनपती है और जब विरोधियों में शक्ति का असन्तुलन पैदा हो जाता है तो आक्रमण का मार्ग खुल जाता है।¹ अतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षों के तकनीकी और अन्य लाभों में सापेक्ष समता बनी रहे, सन्तुलन बिगड़ने न पाए। एक-पक्षीय निःशस्त्रीकरण द्वारा जब शक्ति-शून्यता (A 'Vacuum' of Power) की स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अस्थिरता आने लगती है और सैनिक महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार के विचार के समर्थकों का विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में संघर्ष के अक्सर और विवाद सदैव उपस्थित रहते हैं और युद्ध का तात्कालिक कारण प्रायः यही बनता है कि शक्ति-सन्तुलन बिगड़ जाता है, शक्ति के वितरण में विषमता आ जाती है।

संघर्ष में एक पक्ष मूल्यों के महत्वपूर्ण पुनर्वितरण (Major Redistribution of Values) का पोषक होता है जबकि दूसरा यथापूर्व स्थिति (The Status-quo) बनाए रखना चाहता है अर्थात् जब आक्रमण और सुरक्षा (The Offence and the Defence) के बीच एक स्पष्ट अन्तर हो तो शान्ति एक विशेष प्रकार की विषमता (A certain kind of asymmetry) द्वारा ही कायम रखी जा सकती है अर्थात् शान्ति तभी अधिक सुरक्षित रह सकती है जब अक्रान्तिकारी विरोधी की श्रेष्ठता (Superiority of the Non-revolutionary Antagonist) स्थापित हो जाए। उदाहरणार्थ, विस्टर चर्चिल ने मार्च, 1946 में 'तोह आबरण' की अपनी प्रसिद्ध फुन्टन वक्तृता में कहा था कि सोवियत आक्रमण को केवल वाश्वत्त्व सैनिक श्रेष्ठता के बल पर ही रोका जा सकेगा।²

1 "There is widespread conviction that, whatever other impetuses to war may be present, a careful equilibration of power between antagonists will tend to prevent war while a disequilibrium will invite aggression."

—Rosen & Jones : op. cit., p. 232.

2 "Soviet aggression would be stopped only by Western military superiority."

—Rosen & Jones : Ibid., p. 233.

विषमताओं या असममितियों (Asymmetries) से तात्पर्य औद्योगिक क्षमता, जनसंख्या एवं युद्ध-क्षमताओं के अन्य भौतिक तत्वों के विभिन्न स्तरों से ही नहीं है बल्कि अधिक गतिशील और चल राजनीतिक तत्वों से भी है। मित्र राष्ट्रों को, जो पारस्परिक सुरक्षा हेतु साधनों को संगठित करने के इच्छुक हों, एक सूत्र में बाँधे रखने की योग्यता का विशेष महत्त्व है। आधुनिक जगत् में केवल दो राज्य रूस एवं अमेरिका, अकेले सफ़टो का सामना करने में समर्थ हैं परन्तु संयुक्त कार्यवाही से उन्हें भी अनेक राजनीतिक व रणनीति सम्बन्धी लाभ मिलते हैं। छोटे राज्यों के लिए विषमताओं को दूर करने में सन्धियों को कायम रखना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ इजराइल अमेरिका पर व सीरिया रूस पर आश्रित है।

अन्य महत्त्वपूर्ण तत्व इच्छा है। यदि एक पक्ष लड़ने को उद्यत न हो तो श्रेष्ठ क्षमताएँ व ठोस सन्धियाँ भी विषमताओं की जनक बन जाती हैं। इसके विपरीत सीमित साधनों व समर्थन वाला राज्य भी अपनी क्षमताओं के पूर्ण उपयोग से विषमताओं को रोक सकता है। राजनीतिक विषमताओं को रोकने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों राज्यों में पूर्ण सन्तुलन हो बल्कि केवल समर्थ आश्रामकों को इस बात का पूर्व ज्ञान हो कि विरोध पर विजय प्राप्त करने का मूल्य लाभों से अधिक है। अतएव, सत्ता का असन्तुलन युद्ध का एक कारण है जिसे नियन्त्रित किया जा सकता है।

2. राष्ट्रवाद, पृथक्तावाद और भूमि-अपहरणवाद (Nationalism, Separatism and Irredentism) — राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आन्दोलन युद्ध के दूसरे कारण हैं। राष्ट्रवाद एक सामूहिक समूह बोध है जो विभिन्न व्यक्तियों को एक सूत्र में बाँधता है। राष्ट्र व्यक्ति का सर्वोपरि सम्बन्ध व कर्त्तव्य बन जाता है तथा वैयक्तिक रूप राष्ट्रीय 'हम-समूह' में परिवर्तित हो जाता है।

एक समूह से आवश्यक लगाव दूसरे समूहों से विवाद बन जाता है। सन् 1969 में एक शोध दल ने ऐसे 160 महत्त्वपूर्ण विवादों का उल्लेख किया था जिनके 15 वर्षों में विशाल मात्रा में हिंसा में परिणत होने की प्रबल सम्भावना है। उन विवादों की लम्बी सूची का वर्गीकरण निम्नांकित है—

- (1) राष्ट्रीय विवाद जिनमें जातीय, धार्मिक व भाषाई समूहों के विवाद हैं।
- (2) वर्ग-विवाद जिनमें आर्थिक शोषण के विवाद सम्मिलित हैं।
- (3) अन्य विवाद जो समरूप समूहों व वर्गों के विवाद से परे हैं।

इन विवादों में 70 प्रतिशत राष्ट्रीय व जातीय विवाद हैं जबकि शेष वर्गीय व अन्य विवाद हैं। वस्तुतः युद्ध को जन्म देने की शृंखला में राष्ट्रीयता एक प्रभावी तत्व है जो अन्य कारणों की अपेक्षा रक्तपात के लिए उत्तरदायी है। जाति, भाषा, धर्म व वंश के आधार पर गठित हम-समूहों की सीमा व राजनीतिक माँगों द्वारा ही राष्ट्रीयता व युद्ध में सम्बन्ध स्थापित होता है।

आधुनिक युद्ध में राष्ट्रीय उग्रवाद के दो प्रमुख रूप सुन्नतवा प्रभावी होते हैं—पृथक्तावादी व भूमि-अपहरणवादी रूप। पृथक्तावादी रूप में एक राष्ट्रीय

समूह वर्तमान राज्य से पृथक् होकर एक नए समूह की रचना का प्रयास करना है जबकि भूमि-अपहरणवादी रूप में एक वर्तमान राज्य दूसरे राज्य की भूमि व जनसंख्या का दावा करता है। इन दोनों बातों को कुछ विस्तार से समझ लेना उपयुक्त है—

पृथक्तावाद और युद्ध (Separatism and War)—विश्व के 140 राष्ट्रीय राज्यों में अल्पसंख्यक सम्मिलित हैं। युगों तक अन्य समूहों के साथ रहने हुए भी अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को पृथक् अनुभव करते हैं। यह भावना पृथक्तावादी आन्दोलन में परिणत हो जाती है और राज्य की भूमि में से ही पृथक् भूमि पर पृथक् राज्य की अथवा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के नियन्त्रण से मुक्त आन्तरिक स्वायत्तता की मांग की जाती है। सत्ताहूड राजनीतिक व्यवस्था द्वारा राज्य की राजनीतिक व सीमा सम्बन्धी एकता के हित में पृथक्तावादी मांगों का साधारणतया विरोध किया जाता है। अनेक पृथक्तावादी मांगों के सम्बन्ध में विवाद युद्ध के कारण बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, पाकिस्तान के पूर्वी भाग की बंगला जनता द्वारा सन् 1971 में पश्चिमी भाग से पृथक् होने के लिए युद्ध किया गया जिसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्र बंगलादेश के रूप में नए राज्य का निर्माण हुआ।

इसी प्रकार अनेक राज्यों में भाषा व नस्लों के आधार पर भी पृथक् राज्यों की मांग की जाती है। सघीय राज्यों में, जहाँ परिस्थितिवश प्रत्येक इच्छा द्वारा विभिन्न जन-समूह अपने हितों की रक्षा के लिए सक्रिय हो, वहाँ विवाद खड़े हो जाते हैं तथा पृथक्तावादी आन्दोलनों का जन्म देते हैं।

भूमि-अपहरणवाद एवं युद्ध (Irredentism and War)—भूमि-अपहरणवाद का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अधिक महत्त्व रहा है। वस्तुतः विश्व की समस्त जनसंख्या व घरातल किसी न किसी राष्ट्रीय राज्य की सीमा के अन्तर्गत है तथापि सीमा निर्धारण में (मुख्यतया युद्ध और विजय के द्वारा) प्राकृतिक विभाजनों की उपेक्षा हुई है। राजनीतिक सीमाएँ के आधार जन-समूह के अनुकूल नहीं हैं। बहुत से स्थानों पर एक जन-समूह दो राज्यों की सीमाओं में आ जाता है। इस समूह के पुनः एकीकरण के प्रयास स्वरूप भूमि अपहरणवाद का सघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। उदाहरणार्थ पाकिस्तान काश्मीर पर इसी आधार पर दावा करता है कि वहाँ की जनसंख्या मुस्लिम है। भूमि अपहरणवाद के कुछ दावे तो इस प्रकार के हैं कि सम्पूर्ण राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विलुप्त हो जाएँगे। यद्यपि पृथक्तावाद और भूमि अपहरणवाद वशीय प्रश्नों से प्रारम्भ होते हैं, परन्तु आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों से भी सम्बन्धित होते हैं। आर्थिक समस्याओं के अनिर्दिष्ट इस प्रकार के आन्दोलनों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक नैतिक घर्म-संकट उपस्थित कर दिया है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है, अतः इस प्रकार के संघर्षों को समर्थन मिलता है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक डार्विनवाद (International Social Darwinism)—अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक डार्विनवाद का दर्शन युद्ध का तीव्रतम

सिद्धान्त है। प्राणियों की तरह समाज भी विकसित होते हैं तथा प्रतियोगिता में सबल समाज आगे बढ़ जाते हैं और निर्बल पीछे रह जाते हैं। सम्पत्ता के विकास के लिए सामाजिक डाबिनवादी इसे आवश्यक मानते हैं। युद्ध के परिणामस्वरूप सत्ता की बागडोर निर्बल हाथों से निकल कर सबल और प्रगतिशील हाथों में आ जाती है। यह दर्शन फासीवाद से सम्बन्धित रहा है। मुसोलिनी के शब्दों में "फासीवाद सार्वजनिक शान्ति की सम्भावना अथवा उपयोगिता में विश्वास नहीं करता तथा शान्तिवाद को, जो कायरता एवं समर्पण को प्रोत्साहित करता है, अस्वीकार करता है। केवल युद्ध में ही मानवीय शक्तियों का विवास चरम सीमा तक होता है तथा युद्ध तो उन व्यक्तियों पर जिनमें सामना करने की क्षमता है श्रेष्ठता की मुहर लगाता है।"¹

फासीवाद विभिन्न समाजों के उन प्राणियों को एक समान मानता है जो रक्त सम्बन्धों से बंधे हुए हैं तथा इस दर्शन का निष्कर्ष नाजीवाद है जिसके दो सिद्धान्त जाति तथा सीमा हैं और जो जातियों की समानता में विश्वास न कर उनके अन्तर के अनुपात में उनका मूल्यांकन करता है। जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है पर रहने का स्थान सीमित होने के कारण जातियों को स्थान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक डाबिनवाद विवाद तथा समूहों की विभिन्नताओं को महत्व देता है। फासीवादी व नाजीवादी आन्दोलनों का यद्यपि अन्त हो गया है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक डाबिनवाद का सिद्धान्त सजीव है।

4. संचार-असफलता (Communications Failure)—विवादों के ग्राह्य में संचार-असफलता का सिद्धान्त भी युद्ध का कारण है। राष्ट्र एक दूसरे को अपनी विचारधाराओं के अनुसार देखते हैं जैसा कि शीत-युद्ध के विवादों में प्रायः होता है। इस प्रकार की बोधात्मक विकृतियाँ पारस्परिक सन्देशों को जन्म देती हैं। एक सरकार द्वारा दिए गए सहयोगात्मक सन्देशों के अनुपात में चेतनावनियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। एक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र के विषय में जो मान्यताएँ बनती हैं वे वास्तविकता से परे होती हैं और साक्षी तथा अनुभव के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं बदलती। संचार-असफलता और सुरक्षा का भय अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को बढ़ा कर विनाशकारी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं।

5. शस्त्रस्त्रीय दौड़ (Arms Races)—अनियन्त्रित शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा का दर्शन भी युद्ध का कारण है। विरोधी राष्ट्र पारस्परिक भय के कारण एक दूसरे से डरते हैं तथा एक के द्वारा की गई सुरक्षात्मक कार्यवाही को आश्रमक विचारों से

1 "Fascism above all does not believe either in the possibility or utility of universal peace. It therefore rejects the pacifism which masks surrender and cowardice. War alone brings all human energies to their highest tension and sets a seal of nobility on the peoples who have the virtue to face it." —*Benito Mussolini* quoted by Steven Rosen and Walter Jones : *The Logic of International Relations*, 1974, p. 242-243.

प्रभावित समझा जाता है और उसके प्रत्युत्तर में शस्त्रों से सुसज्जित होने का प्रयत्न किया जाता है। शस्त्रों तथा संगठित सैनिक संगठनों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है एवं प्रत्येक पक्ष श्रेष्ठता के लिए प्रयत्नशील रहता है। गणितीय अध्ययन के अनुसार शस्त्रास्त्रों की दौड़ सक्रिय विवादों को जन्म देती है और परकाष्ठा पर पहुँच कर विस्फोटक हो जाती है। उदारवादी विचारकों के अनुसार अत्यधिक संख्य सज्जा तथा शस्त्रास्त्रों का सचय युद्ध के कारण है जबकि अनुदारवादियों की मान्यता है कि ये शान्ति को प्रोत्साहित करने में सहायक हैं। नारमन कजिस द्वारा दिए गए कम्प्यूटर अध्ययन के अनुसार 650 ई. पू. से अब तक 1956 शस्त्रास्त्रों की होड़ों में से केवल 16 युद्ध में परिणत नहीं हुईं तथा इन अपवादों में से अधिकांश धार्मिक संकट का शिकार बनीं। सैम्युअल पी. हटिंगटन के अध्ययन के अनुसार शस्त्रास्त्रों की दौड़ युद्ध की प्रस्तावना अथवा विवक्षित सिद्ध हुई। शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा और युद्ध में महत्वपूर्ण निवृत्ति होते हुए भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शस्त्रास्त्रों की दौड़ के परिणामस्वरूप युद्ध हुए। महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद ही शस्त्रास्त्र की दौड़ तथा युद्ध के कारण हैं। शस्त्रों की दौड़ तथा भय वर्तमान विवादों की धमि में भी का काम करते हैं परन्तु नए विवाद इनके कारण उत्पन्न नहीं होते।

6 बाह्य संघर्ष के माध्यम से आन्तरिक एकीकरण (Internal Cohesion through External Conflict)—इस सिद्धान्त के अनुसार युद्ध आन्तरिक सामूहिक एकीकरण की अभिवृद्धि की नीतियों के परिणामस्वरूप होते हैं। बाह्य संघर्ष के माध्यम से आन्तरिक एकीकरण की दिशा में किए गए प्रयास कालान्तर में युद्ध को जन्म देते हैं—समुक्त शत्रु का सामना करने के लिए एकीकरण की प्रक्रिया युद्ध को बढ़ावा देती है। सन् 1866 से 1871 के मध्य विस्मार्क द्वारा प्रोत्साहित तीनों युद्ध जर्मन राज्यों के एकीकरण के उद्देश्य से लड़े गए थे। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आन्तरिक विघटन की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध पसन्द किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार आन्तरिक एकीकरण तथा बाह्य संघर्ष में सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता।

7. स्वतः प्रेरित आक्रमण (Instinctual Aggression)—आक्रमण की भावना का सिद्धान्त युद्ध के सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धान्तों में से है। मानव का स्वभाव युद्धप्रिय होता है। हिंसा में उसे आनन्द की अनुभूति होती है, इसीलिए टेलीविजन तथा चलचित्रों में लड़ाई और हिंसा को प्रदर्शित किया जाता है। आक्रामक भावना और युद्ध के निश्चय के सम्बन्ध के विषय में मतभेद है। 25 युद्धों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि भावनाओं के कारण युद्ध करने का निश्चय नहीं किया गया। अन्य विचारक आक्रमण को भावना से सम्बन्धित करते हैं। राजनीतिक विवादों को छेड़ने में आक्रामक भावना बलवती रही है जिससे युद्ध का निश्चय किया गया।

क्रमबद्ध अध्ययन वास्तविक तथा अवास्तविक विवादों में अन्तर करता है। वास्तविक विवाद में संघर्ष का कारण उद्देश्य सम्बन्धी मतभेद होता है जबकि अवास्तविक विवादों में अन्य कारण तो बहाना मात्र होते हैं और लड़ने वालों का

मुख्य उद्देश्य हिंसा रहता है। कुछ विचारकों के अनुसार आक्रमण की समस्या का समाधान आक्रमण भावना को नष्ट करने में न होकर उसे रचनात्मक दिशा प्रदान करने में है। आक्रामक भावनाएँ राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में सहायक होती हैं तथा राष्ट्रीय विचारधारा को प्रभावित करती हैं। विभिन्न संस्कृतियों के आक्रामक व्यवहार में भिन्नता होती है।

8 आर्थिक और वैज्ञानिक उद्दीपन (Economic and Scientific Stimulation)—युद्ध का अन्य सिद्धान्त आर्थिक कार्यों से सम्बन्धित है। युद्ध ने वैज्ञानिक खोज, तकनीकी सुधार व औद्योगिक विकास को गति प्रदान की है। कुछ विचारक यह मानते हैं कि सैन्य व्यय उचित है और उसमें कटौती करने से अनेक उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि यह मान लिया जाए तब भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि युद्ध व्यापार के लिए उचित है। बड़े युद्धों के आर्थिक दुष्परिणाम निकलते हैं, मुद्रा-प्रसार की अभिवृद्धि होती है, साख घट जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं तथा आर्थिक प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। चाहे युद्ध लाभकारी भले ही न हो, परन्तु रक्षात्मक व्यय पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। आर्थिक लाभ की दृष्टि में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना लाभकर होता है। युद्ध का प्रारम्भ न हो तब भी रक्षात्मक व्यय शीतयुद्ध को कायम रखने में सहायक होता है।

9. सैनिक औद्योगिक समूह (Military-Industrial Complexes)—सैनिक-औद्योगिक समूह भी युद्ध का कारण बन जाते हैं। शक्तिशाली आन्तरिक समूह, जिनके हित सैन्य-व्यय में निहित होते हैं, राष्ट्रों में तनाव व विरोध बनाए रखने में अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। इन आन्तरिक समूहों में सैनिक-औद्योगिक संस्थाएँ सम्मिलित हैं—(1) व्यावसायिक सिपाही, (2) व्यवस्थापक तथा पूँजीवादी राज्यों में सैन्य उद्योगों के स्वामी, (3) राज्य के उच्च अधिकारी जिनके हित सैन्य-व्यय से जुड़े हुए होते हैं, तथा (4) विधायक जिनके निर्वाचन-क्षेत्रों की रक्षात्मक योजनाओं से लाभ पहुँचता है। इन सैनिक-औद्योगिक संस्थानों के सदस्यों को अन्य छोटे समूहों का समर्थन भी प्राप्त होता है। शनैः-शनैः ये समूह राजनीतिक व्यवस्था में अपना प्रभाव बढ़ा लेते हैं तथा रक्षात्मक व्यय की राशि में कटौती नहीं होने देते एवं राष्ट्रीय सुरक्षा-नीति के निर्माण को प्रभावित करते हैं। विरोधी हितों की तुलना में इन संस्थानों का प्रभाव अधिक होता है। सैन्य-व्यय के लिए ये वैज्ञानिक विवाद खड़े कर देते हैं तथा शीतयुद्ध जैसी स्थिति को यथावत् बनाए रखने में अपने हितों का संरक्षण मानते हैं।

यह सिद्धान्त पूँजीवादी व समाजवादी व्यवस्थाओं में समान रूप से प्रियामात्र रहता है। इसमें कुछ दोष हैं। राष्ट्रीय उत्पादन में कमी होने के कारणों पर इन सिद्धान्त का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता। फिर भी आर्थिक नीतियों के निर्माण में इन संस्थानों का बहुत योगदान होता है।

10 सापेक्ष वंचन (Relative Deprivation)—सापेक्षिक वंचन का सिद्धान्त आन्तरिक युद्धों के कारणों का विश्लेषण करने में सहायक होता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उन्हें उचित लाभ नहीं मिल रहा है तो राजनीतिक विद्रोहों तथा विप्लवों को प्रोत्साहन मिलता है तथा अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से राजनीतिक हिंसा व आक्रामक कार्यवाही की ओर झुकाव बढ़ता है। परन्तु देखा गया है कि निर्धनता तथा अत्याचार प्रत्यक्षतः विद्रोहों को जन्म नहीं देते, बल्कि इन दशाओं का मनोवैज्ञानिक प्रत्युत्तर निश्चित करते हैं। प्रायः हिंसा तब फैलती है जब स्थितियों में सुधार हो रहा होगा है, न कि तब जबकि स्थितियाँ खराब होनी हैं। सन् 1945 के बाद में लड़ी गई लड़ाइयाँ विकासशील देशों में हुईं न कि विकसित देशों में। विकसित देशों में इस काल में केवल छुटपुट घटनाएँ ही हुईं। धनी देश अपनी सीमाओं से परे अन्य देशों के विवाद में पड़ जाते हैं।

11. जनसंख्या सीमा (Population Limitation)—जनसंख्या में वृद्धि युद्धों को जन्म देती है। खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि अधिक होती है। खाद्यान्नों की मात्रा के अनुसार जनसंख्या को नियन्त्रित किया जाना चाहिए और युद्ध द्वारा यह नियन्त्रण सम्भव है। परन्तु यह सिद्धान्त तथ्यों पर आधारित नहीं है। युद्धों में अधिक सरया में व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होती। केवल अपवाद स्वरूप कुछ युद्धों में ही अधिक संख्या में जीवन का विनाश हुआ, परन्तु वहाँ भी अधिकाधिक 5 प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु ही हुई। हरित क्रान्ति द्वारा खाद्यान्नों में अधिक मात्रा में वृद्धि सम्भव है तथा जनसंख्या के नियन्त्रण की समस्या उत्पन्न नहीं होती।

12. संघर्ष संकल्प (Conflict Resolution)—युद्ध विवादों के हल में सहायक होते हैं। सामान्यतया दो अथवा दो से अधिक समूह किन्हीं साधनों तथा स्थितियों पर अपना-अपना दावा करते हैं तथा ऐसी स्थिति में युद्ध द्वारा समस्याएँ हल होती हैं। युद्ध विवादों के निर्णय का तात्कालिक माध्यम है तथा युद्ध-नीतियाँ उत्पादन-व्यय और लाभ की दृष्टि से निर्मित की जाती हैं। परन्तु यह विवादास्पद प्रश्न है। विवादों का हल पंच फैसले, चुनाव, अदालतों तथा प्रशासनिक निर्णयों द्वारा भी सम्भव है। सीधी वार्ता मध्यस्थता तथा समझौतों के द्वारा भी विवादों को हल किया जा सकता है। फिर भी अन्ततः युद्ध द्वारा विवादों के हल का प्रयास किया गया है।

युद्ध के 12 कारणों के अतिरिक्त पड़यन्नों, छिपे उद्देश्यों तथा गुणी लोगों के प्रभाव के कारण भी युद्ध लड़े जाते हैं।

स्टीड (Wickham Steed) ने युद्ध के कारणों में 'भय' को प्रधान माना है। असुरक्षा की भावना निश्चय ही आज के विश्व में युद्ध का सबसे प्रमुख कारण है। दूसरे विचारक 'सम्प्रभु' राज्यों के अस्तित्व को युद्ध का प्रमुख कारण मानते हैं। आर्नल्ड ब्रेच्ट (Arnold Brecht) ने लिखा है कि राज्यों के बीच युद्ध होते हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि विश्व में सम्प्रभु राज्य हैं। इसी बात पर टिप्पणी करते हुए क्विंसी राइट ने कहा है कि युद्ध का कारण सम्प्रभु राज्यों का

6. युद्ध आधुनिक विश्व का निर्माता है—बहा जाता है कि युद्ध द्वारा एक राष्ट्र के व्यक्तित्व का सही ग्रंथों में निर्माण होता है। युद्धों के द्वारा ही एक राष्ट्र की सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं। प्रोफेसर शांटवैस का कथन है कि आज के विश्व का नक्शा अधिकांशतः युद्ध के मैदानों में ही निश्चित किया गया है। क्विंसी राइट (Quincy Wright) के मतानुसार युद्ध को विश्व के महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों के लिए, राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण के लिए, आधुनिक सभ्यता का विश्व-व्यापी प्रसार करने के लिए तथा उस सभ्यता के प्रभावकारी हितों को परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया गया है। कानून, विदेश-नीति, सैनिक, तरुनीकी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कुछ परिस्थितियों में युद्ध 'नीति का एक मूल्यवान साधन' बन जाता है। पामर तथा पकिंस के शब्दों में, "संक्षेप में युद्ध आधुनिक विश्व का उसके राज्यों, कारखानों, इसकी नैतिकता और इसके सांस्कृतिक रूप का प्रमुख निर्माता रहा है।"

7. युद्ध व्यक्ति को ऊँचा उठाता है—युद्ध के जान-माल का जो विनाश होता है वह व्यक्ति के मन में इन वस्तुओं की नश्वरता के भाव जाग्रत करता है। अतः वह स्वार्थ, परिग्रह, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों के स्थान पर उदार, निर्भीक तथा अपरिग्रही बनता है; उसमें वलिदान करने की शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, युद्ध के कारण व्यक्ति की नैतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताएँ प्रखर होकर प्रकाश में आती हैं। भारत-पाक संघर्षों ने भारतीयों के साहस, मनोबल और आत्म-त्याग को कितना ऊँचा उठाया है, यह प्रकट तथ्य है। प्रायः दवाइयाँ कड़वी होती हैं, किन्तु रोग को दूर करने व स्वास्थ्य में निखार लाने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार युद्ध ही भी कुछ बुरे परिणाम होते हैं, किन्तु देश के व्यक्तित्व के निर्माण में यह बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। तिरस्कापूर्ण एवं भ्रष्ट शान्ति की अपेक्षा सम्मानपूर्ण युद्ध श्रेष्ठ है जो आत्म-वलिदान, समानता, ईश्वर-प्रेम, परार्थ, राष्ट्रीय एकाता आदि भावों का विकास करता है।

8. युद्ध विकास को सही दिशा देता है—डाविन ने जीव-विकास के सम्बन्धों में दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था। उन्हीं के आधार पर यह बहा जाता है कि युद्ध राष्ट्रों के सही विकास के लिए आवश्यक है। युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कमजोर राष्ट्रों का उन्मूलन कर देती है तथा शक्तिशाली लोगों के उन्नति व विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। बर्नार्डी (Bernhardi) के मतानुसार युद्ध प्रथम महत्त्व की प्राणिशास्त्रीय आवश्यकता है। बिना युद्ध के कमजोर जातियाँ स्वस्थ तत्त्वों के विनाश को रोक देंगी तथा सामान्य रूप से पतन प्रारम्भ हो जाएगा।¹

युद्ध के उपर्युक्त कारणों अथवा लाभों की अतिशयोक्ति बता कर इनकी प्रालोचना की जा सकती है, किन्तु इनको पूरी तरह से अमर्य नहीं माना जा सकता।

विलर्ड वाटर (Willard Waller) के मतानुसार युद्ध से कोई लाभ नहीं है तथा किसी भी समस्या को इसके द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता; किन्तु पामर तथा पकिंस का कहना है कि प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि युद्ध के द्वारा कभी-कभी अनेक लाभ प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए युद्ध का विरोध करते समय यह तर्क देना अनुचित है कि इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता या इसका कोई उपयोग नहीं है वरन् कहना यह चाहिए कि युद्ध एक अमानवीय तथा जगली साधन है जिसका उपयोग यथासम्भव अच्छे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी नहीं करना चाहिए।

सम्पूर्ण युद्ध (The Total War)

आधुनिक युद्ध के स्वरूप को देख कर इन्हे समग्र युद्ध की संज्ञा प्रदान की जाती है। माँगैन्थो ने स्वीकार किया है कि आधुनिक युद्धों को चार कारणों में सम्पूर्ण युद्ध कहा जा सकता है। प्रथम, इसलिए कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भावनाओं तथा प्रेरणाओं की दृष्टि से पूर्णतः एकरूप होकर राष्ट्रीय युद्धों में लग जाता है। दूसरे, युद्ध में योगदान करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है। तीसरे, युद्ध से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं और चौथे, युद्ध द्वारा जिन उद्देश्यों की साधना के लिए प्रयास किए जाते हैं वे अत्यन्त व्यापक होते हैं। इन सभी दृष्टियों से पहले युद्ध सीमित हुआ करते थे क्योंकि उनको थोड़े ही लोगों का भावनात्मक एवं सैद्धान्तिक सहयोग प्राप्त होता था; युद्ध में सक्रिय रूप से बहुत थोड़े लोग लड़ते थे, युद्ध से प्रभावित होने वाली जनसंख्या अधिक नहीं होती थी और युद्ध के उद्देश्य भी सीमित होते थे; किन्तु आज स्थिति पूर्णतः विपरीत है।

1. वर्तमान युग में जब युद्ध होता है तो देश के समस्त नागरिक युद्ध के साथ स्वयं की एकरूप कर लेते हैं। यह एकरूपता नैतिक एवं अनुभूतिपरक तत्वों के आधार पर स्थापित की जाती है। नैतिक तत्त्व न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धान्त की बीसवीं शताब्दी की पुनर्गठित है। इसके अनुसार युद्ध में सलग दो राज्यों के बीच भेद करते हुए यह निश्चित किया जाता है कि कौन कार्य कानून और नैतिकता की दृष्टि से न्यायोचित है तथा किसको कानूनी तथा नैतिक दृष्टि से हथियार उठाने का अधिकार नहीं है। यह सिद्धान्त मध्ययुग में अत्यन्त प्रभावी था, किन्तु आधुनिक राज्य-व्यवस्था के जन्म ने इस पर पानी फेर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप एक नया सिद्धान्त विकसित हुआ जो प्रत्येक प्रकार के युद्ध को न्यायोचित ठहराता है। सीमित युद्धों में न्यायोचित और अन्यायपूर्ण युद्ध के बीच का अन्तर अस्पष्ट रूप से बना रहा, किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब युद्ध को एक तथ्य मात्र समझा जाता है जिसके आचरण के नैतिक एवं कानूनी नियमों की रचना राज्य अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। इस प्रकार युद्ध राष्ट्रीय एवं शासकों के व्यक्तिगत हित का साधन बन गया है जिसे कूटनीति के साथ समुक्त किया जाता है।

इस प्रकार के युद्ध के साथ जनता स्वयं को एकाकार करने में कठिनाई अनुभव करती है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब युद्ध के उद्देश्य को नैतिक सिद्ध कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में, यह कहा जाता है कि शत्रु के विरुद्ध तथा अपने समर्थन में नैतिक उत्साह प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि अपने पक्ष को न्यायोचित बनाया जाए और दूसरे पक्ष को अन्याय पर आधारित ठहराया जाए। सम्भव है कि जो भाग्यवश या व्यावसायिक सैनिक हैं वे बिना इस सबके युद्ध में अपनी जान दे दें, किन्तु शस्त्र धारण करने वाले सामान्य नागरिक बिना इसके अपने नहीं बढ़ सकते। उन्नीसवीं शताब्दी में नैपोलियन के युद्धों में तथा इटली और जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के युद्धों में राष्ट्रवाद की भावना ने न्याय के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

जिस समय युद्धों के पीछे कोई नैतिक या कानूनी सिद्धान्त कार्य नहीं करता या उस समय कोई भी सेना कभी भी लड़ना बन्द कर सकती थी क्योंकि लड़ने वालों की प्रेरणा का स्रोत केवल धन था। युद्ध के पूर्व सेना उस पक्ष का समर्थन छोड़ कर जिससे उसने बेतन प्राप्त किया है दूसरे गुट में मिल जाती थी। सोलहवीं एवं सत्रहवीं शताब्दी के धार्मिक युद्धों में तो पूरी की पूरी सेना कई बार पक्ष बदल लेती थी।

पहले सैनिक सेवा को अपराधों के लिए दण्ड स्वरूप प्रयुक्त किया जाता था। जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती थी उनके सम्मुख एक विकल्प यह होता था कि वे चाहे तो सेना में भर्ती हो जाएँ। इस प्रकार संगठित सेना में मनोबल जैसी किसी चीज के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे लोग न तो अपने देश के प्रति स्वामिभक्ति रखते थे और न ही अपने राजा के प्रति स्वामिभक्त थे। इन लोगों को केवल कड़े अनुशासन और इनाम के आधार पर साथ रखा जाता था। उस समय के युद्धों की प्रकृति, सैनिकों का सामाजिक सम्मान तथा सामाजिक पृष्ठ-भूमि आदि के सन्दर्भ में ऐसा होना स्वाभाविक ही था।

सीमित युद्धों के समय जब युद्ध सिंहासन-प्राप्ति के लिए या किसी नगर की प्राप्ति के लिए या राजा के सम्मान के लिए लड़े जाते थे, वहाँ सैनिक सेवा को राजा का वंश-परम्परागत विशेषाधिकार समझा जाता था, किन्तु सन् 1793 के फ्रांसीसी कानून ने जब 18 और 25 के प्रत्येक स्वस्थ पुरुष के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी तो युद्ध के नए स्वरूप को पहली बार व्यवस्थापिका की मान्यता प्राप्त हुई। फ्रान्स की भक्ति प्रशा (Prussia) ने सन् 1807 में कानून पारित किया जिसके अनुसार भाड़े के सैनिकों तथा में विदेशियों को लेना बन्द कर दिया गया और सन् 1814 के कानून के अनुसार अपने देश की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य घोषित कर दिया। इस प्रकार युद्ध का स्वरूप ऐसा हो गया जिसमें सारा जनता भाग लेती है।

2. समग्र युद्ध की दूसरी विशेषता यह है कि यह युद्ध केवल सम्पूर्ण जनता का ही नहीं होता बरन् सम्पूर्ण जनता द्वारा लड़ा जाता है। जब बीसवीं शताब्दी में युद्ध का स्वरूप परिवर्तित हो गया और इसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय मुक्ति न होकर राष्ट्रवादी विश्व-व्यापकता हो गया तो युद्ध में जनता का योगदान भी अपेक्षाकृत बढ़

गया। अब न केवल स्वस्थ पुरुषों को ही युद्ध में लिया जाता है बल्कि सर्वाधिकारवादी देशों में तो स्त्रियों और बच्चों को भी युद्ध में भाग लेना पड़ता है। गैर-सर्वाधिकारवादी देशों में भी स्त्रियों की सेवाएँ उनकी स्वेच्छा के आधार पर माँगी जाती हैं। हर देश में राष्ट्र की भी शक्तियाँ युद्ध में लगा दी जाती हैं। सीमित युद्ध के समय अधिकांश जनता का युद्ध से कुछ सम्बन्ध नहीं होता था। सामान्य जनता पर तो केवल यह प्रभाव पड़ता था कि उससे अधिक कर लिए जाते थे, किन्तु आज का युद्ध प्रत्येक व्यक्ति का युद्ध है और उसे इसमें अपना सक्रिय योगदान देना होता है।

इस विकास के लिए उत्तरदायी दो कारण माने जाते हैं। प्रथम यह कि सेनाओं के आकार में वृद्धि हो गई है और दूसरे यह कि युद्ध का यान्त्रिकीकरण हो गया है। सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारवीं शताब्दियों में सेनाओं का आकार बढ़कर अधिक से अधिक दस हजार हो जाता था। नैपोलियन के युद्धों में कुछ सेनाओं की संख्या कुछ लाख व्यक्तियों तक हो गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध में पहली बार सेनाएँ दस लाख से ऊपर पहुँच गईं और द्वितीय विश्वयुद्ध में इनकी संख्या एक करोड़ से ऊपर हो गई। युद्धों में हथियारों, आवश्यक सामग्री, यातायात एवं संचार साधनों आदि का यन्त्रीकृत रूप तथा सेवा का विशाल आकार आज यह माँग करता है कि कार्य करने वाली समूची जनसंख्या अपना पूरा योगदान दे। ऐसा होने पर ही सैनिक संस्थान को युद्ध के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि युद्धभूमि में एक व्यक्ति को सक्रिय रखने के लिए कम से कम एक दर्जन व्यक्तियों के उत्पादनशील प्रयासों की आवश्यकता रहती है। युद्ध-भूमि में लड़ रहे सैनिकों के लिए भोजन, वस्त्र तथा हथियार मुहैया कराने, यातायात और संचार की व्यवस्था करने आदि कार्यों में जितने लोगों को सक्रिय होना पड़ता है उसके आधार पर यह कहना कोई अनिवार्यता नहीं होगी कि वर्तमान युद्ध सम्पूर्ण जनता के युद्ध बन गए हैं।

3. युद्धों को समग्र कहने का एक तीसरा आधार यह है कि ये सम्पूर्ण जनसंख्या के विरुद्ध लड़े जाते हैं। केवल यही नहीं कि प्रत्येक युद्ध में भाग लेना पड़ता है बल्कि प्रत्येक के युद्ध का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। किसी भी युद्ध में होने वाली क्षति के आँकड़े यद्यपि कम विश्वसनीय होते हैं, तथापि वे इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। पहले युद्धों में जनसंख्या का जो प्रतिशत अपनी जान से हाथ धोता था वह आज की अपेक्षा बहुत कम था। बीसवीं शताब्दी में युद्ध का स्वरूप विध्वंसक बन गया है, इसलिए सैनिक कार्यवाही से होने वाले हताहतों की संख्या भी अपेक्षाकृत बढ़ गई है। धार्मिक युद्धों की समाप्ति के बाद से ही गैर-सैनिक जनता को भी युद्धों के दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। इनमें कोई सन्देह नहीं है कि द्वितीय विश्वयुद्ध की सैनिक कार्यवाही से सामान्य नागरिकों की जितनी जानें गईं वे सैनिकों की तुलना में अधिक थीं। द्वितीय विश्वयुद्ध ने मे सोवियत संघ के हताहतों की संख्या उनकी कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत थी। इस प्रकार आधुनिक युद्धों में गैर-सैनिक लोगों के हताहत होने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है।

4. आज के युद्धों को लक्ष्य की दृष्टि से भी समग्र युद्ध कहा जाता है। आज विश्व की महान् शक्तियाँ केवल इसलिए युद्ध नहीं लड़ती कि वे युद्ध-क्षेत्र में शत्रु की सेनाओं को हरा दें या अपनी क्षतिपूर्ति कर लें अथवा अपनी सीमाओं का विस्तार कर लें। आज के युद्धों का उद्देश्य शत्रु देश की जनता का पूर्ण विनाश होता है, उसके कल-कारखानों एवं युद्ध-क्षमता को समाप्त करना होता है, उसकी सरकार का पुनर्गठन होता है तथा उस देश की विचारधारा को बदलना होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में हारने वाले लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन तक को परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा परिवर्तन जापान में मित्र राष्ट्रों द्वारा और केन्द्रीय यूरोप में सोवियत संघ द्वारा किया गया।

युद्ध के आधुनिक स्वरूप में सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को भी समाहित किया जाता है। मुक्ति के लिए युद्ध (Wars of Liberation) असुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं और ये न केवल विजित राष्ट्रों में वरन् तटस्थ एवं विजयी राष्ट्रों में भी छेड़ जा सकते हैं। युद्ध द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न की जाती है, वह सैनिक पराजय के बिना भी क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देती है। आधुनिक समग्र युद्ध में पूर्ण पराजय की जोखिम रहती है। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध में असीमित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए असीमित सैनिक साधनों का प्रयोग किया गया। इस दृष्टि से यह सुझाया जाता है कि यदि हम युद्ध में अपनाए जाने वाले साधनों के प्रयोग को सीमित करना चाहते हैं तो हमें लक्ष्यों को भी सीमित करना होगा।

आज के युद्ध विश्व-विजय को अपना उद्देश्य बना कर भी लड़े जाते हैं। अनेक यान्त्रिक विकासों के परिणामस्वरूप यातायात, मंचार और शस्त्रों के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसने विश्व-विजय तथा विजयी राष्ट्र द्वारा उसकी व्यवस्था को भी सम्भव बना दिया है। यह सच है कि इससे पहले भी बड़े-बड़े साम्राज्य थे, किन्तु साम्राज्य अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सके, क्योंकि उस समय ऐसे यान्त्रिक साधनों का अभाव था जिनसे व्यापक जनता पर नियन्त्रण रखा जा सके।

एक विश्वव्यापी साम्राज्य को स्थायी रूप देने के लिए तीन चीजें मूल रूप से आवश्यक हैं। प्रथम, साम्राज्य के सभी लोगों के मस्तिष्क पर केन्द्रीकृत नियन्त्रण द्वारा सामाजिक एकीकरण लागू करना; दूसरे, साम्राज्य में जहाँ भी वही एकता के विरोध की सम्भावना हो वहाँ सर्वोच्च संगठित सेना रखना और तीसरे, नियन्त्रण एवं प्रभाव के इन साधनों में स्थायित्व लाना तथा सम्पूर्ण साम्राज्य में विस्तृत करना। इन तीनों सैनिक एवं राजनीतिक पूर्व-प्रावश्यकताओं में से प्रत्येक काल में एक भी प्राप्त नहीं की जा सकी; किन्तु आज ये तीनों ही सम्भव हैं।

पहले मंचार के साधन गैर-यान्त्रिक थे और जहाँ वही यान्त्रिक थे वहाँ वे कठोर रूप से बंयक्तिक और इस प्रकार विकेन्द्रीकृत थे। ऐसी स्थिति में भावी विजयों की धमक विरोधियों से लड़ना होता था। विश्व-विजय की कामना रखने वाला यदि

अपने विरोधियों को पकड़ ले और पहचान ले तो उन्हें जेल में डाल सकता था, उनकी हत्या करा सकता था; किन्तु यह नहीं कर सकता था कि उनकी जवान को गरम बना दे या समाचार, रेडियो एवं चलचित्रों पर एकाधिकार कर ले।

पहले हिंसा के साधन भी बहुत कुछ गैर-यांत्रिक, विवेकशील और व्यक्तिगत थे। ऐसी स्थिति में विश्वव्यापी साम्राज्य बनाने का स्वप्न देखने वाला पग-पग पर ऐसे संगठनों को खड़ा पाता था जो उससे लगभग समान-स्तर चाहते थे। दोनों के पास समान हथियार थे। ऐसी स्थिति में कोई भी विजेता साम्राज्य की स्थापना के लिए सभी सम्भावित विरोधियों के विरुद्ध हर जगह एक सर्वोच्च संगठित सेना संगठित नहीं कर सकता था। पहले के साम्राज्य का कोई भी शत्रु कहीं विद्रोह कर दे तो उसे दबाना दुष्कर होता था, क्योंकि केन्द्रीय सत्ता को इसकी सूचना बहुत दिनों में प्राप्त होती थी और सूचना मिलने के बाद भी विद्रोह को दबाने के लिए जो प्रयास किया जाता था उसमें भी पर्याप्त समय लग जाता था; किन्तु आज की स्थिति में कोई भी विश्व सरकार रेडियो के माध्यम से शीघ्र ही वस्तु-स्थिति से परिचित हो जाएगी और कुछ ही घंटों में सैकड़ों व्यक्तियों को भेज देगी तथा गैरापूट मोर्टार, टैंक तथा हथियारों से भरे हुए बीसियों पग भिजवा देगी जिन पर उसका एकाधिकार है और इस प्रकार राजद्रोह-प्रस्त नगर की स्थिति पर काबू पा लेगी।

आज यातायात के क्षेत्र में होने वाले आविष्कारों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि विश्व-साम्राज्य की स्थापना करने वाले को अनुकूल जलवायु और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता जिसके कारण नेपोलियन के प्रयास निरर्थक बन गए थे और विश्व-विजय का विचार रखने वाले अन्य नेताओं ने अपना साहस खो दिया था।

आज की स्थिति में सम्भावित विश्व-विजेता के पास तकनीकी साधन हैं जिनके द्वारा वह एक बार की गई प्राप्ति को स्थायी बना सकता है। जीते हुए प्रदेश में उसकी संगठित सेना की सर्वोच्चता हर समय और हर जगह मानी जाएगी इसमें भीसम और दूरी कुछ भी बाधक नहीं बन सकेंगे। संचार के सशक्त साधनों द्वारा विजेता अपने सम्भावित शत्रुओं पर सर्वोच्चता कायम कर सकता है। इस प्रकार यदि एक बार किसी ने विश्व-साम्राज्य स्थापित कर लिया तो वह उसकी स्थिर रख सकता है और सकल रूप में उसका संचालन कर सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को एक बार जीत लिया गया वे हमेशा के लिए विजित बनाए जा सकते हैं। आज यदि एक देश प्रभावपूर्ण तकनीकी के साधनों में सर्वोच्चता रखने में सक्षम है तो वह विश्वव्यापी साम्राज्य भी स्थापित कर सकता है। यदि एक राष्ट्र अणुशक्तों पर और संचार तथा यातायात के प्रमुख साधनों पर एकाधिकार रख सके तो वह दुनिया को जीत सकता है और इस जीत को स्थायी बना सकता है किन्तु यह तभी सम्भव है जबकि वह इस एकाधिकार और नियन्त्रण को कायम रखने में समर्थ हो। आधुनिक तकनीक ने यह सम्भव बना दिया है कि

दुनिया के प्रत्येक कोने के लोगों के दिमाग और कारों पर प्रत्येक मौसम में नियन्त्रण रखा जा सकता है।

सैनिक शक्ति की सम्भावनाएँ

(The Possibilities of Military Power)

सैनिक शक्ति एक देश की रचना का आवश्यक अंग होती है जिसके बिना वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। राज्य के जो चार आवश्यक तत्व माने गए हैं उनमें महत्त्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सम्प्रभुता का स्थान सर्वोपरि माना जाता है और किसी भी राज्य की सम्प्रभुता उसकी सैनिक सामर्थ्य एवं सम्भावनाओं द्वारा तय की जाती है। सैनिक शक्ति को सम्भावनाओं का चार शीर्षकों के अन्तर्गत वर्णन किया जा सकता है—

1. आक्रमणकारी क्षमता (The Offensive Capability)—राज्य अपने पड़ोसियों के विरुद्ध प्रायः आक्रमणकारी युद्ध सड़ते रहते हैं। राज्यों द्वारा अनेक राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य गुप्त उद्देश्यों के लिए युद्ध किए जाते हैं। सैनिक शक्ति के प्रयोग के ये उद्देश्य प्रायः अप्रत्यक्ष रूप में छिपे रहते हैं। प्रारम्भ में इन युद्धों का स्वरूप एवं प्रभाव सीमित था।

इतिहास साक्षी है कि आक्रमणकारी युद्धों ने आक्रमणकारियों को अनेक लाभ प्रदान किए। राज्य ने सैनिक शक्ति के प्रयोग के बल पर अपनी स्वतन्त्रता को बचाना रखा। अनेक राज्यों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और अपनी धन-सम्पदा को भी सैनिक शक्ति के बल पर व्यापक बना लिया। अतीत में सैनिक शक्ति द्वारा राज्यों ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का मफल प्रयास किया और वर्तमान सशस्त्र संघर्षों द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रों ने सैनिक शक्ति द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि का मार्ग त्यागा नहीं है। कई बार विभिन्न कारणों से आक्रमणकारी को भागी समझना पड़ा भी मिलती है। आक्रमणकारी को बड़ा लाभ यह रहता है कि वह आक्रमण के स्थान, समय एवं प्रकार को निश्चित करने का अवसर प्राप्त कर लेता है। आधुनिक शस्त्रों के आविष्कार ने आक्रमणकारी की शक्ति को पर्याप्त लाभदायक स्थिति में रख दिया है।

प्रत्येक आक्रमणकारी को अपने आक्रमण के सम्बन्ध में अनेक निर्णय लेने होते हैं। वही यह तय करता है कि आक्रमण द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, किन हथियारों या शक्तियों का प्रयोग करना है, किन भौगोलिक क्षेत्रों को सम्मिलित करना है और किनको अलग करना है, युद्ध में रणनीति से काम लेना है अथवा कूटनीति में। कूटनीति युद्ध का अर्थ उस युद्ध से है जिसमें शत्रु की सशस्त्र सेना पर आक्रमण किया जाता है और रणनीति युद्ध वह होता है जो शत्रु की अर्थ-व्यवस्था एवं गृह-व्यवस्था को नष्ट करने के लिए किया जाता है। युद्ध के उद्देश्य एवं पद्धति को निश्चय करने के बाद ही प्रायः यह निर्णय किया जाता है कि कौन से हथियारों का प्रयोग करना होगा।

आक्रमणकारी को यह स्वतन्त्रता रहती है कि वह प्रसीमित युद्ध छेड़ सकता है, शत्रु से बिना शर्त आत्मसमर्पण की माँग कर सकता है, घातक शस्त्रों का प्रयोग कर सकता है तथा भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता है। वह चाहे तो अपने कार्यों को पर्याप्त भी कर सकता है, सीमित युद्ध पद्धति अपना सकता है, कम हथियारों का प्रयोग कर सकता है, शत्रु की धर्म-व्यवस्था को छुए बिना केवल मैना पर आक्रमण कर सकता है, आदि-आदि। इस प्रकार आक्रमणकारी द्वारा किए जाने वाले आक्रमण कई श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं; जैसे, सर्वविनाश के लिए आक्रमण, परम्परागत आक्रमण, शीत-युद्ध एवं गृह-युद्ध। बाद वाली श्रेणियों के बीच भ्रान्त करना असम्भव है क्योंकि किसी भी गृह-युद्ध में किसी भी महाशक्ति का ध्यान भाङ्गित हो सकता है।

2. सुरक्षात्मक क्षमता (Defensive Capability)—शत्रु के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की सैनिक-क्षमता का एक मुख्य उद्देश्य सम्भ्रा जाता है। आज के युग में एक प्रभावशाली सुरक्षा-व्यवस्था यह होती है जिसमें पहले की अपेक्षा बड़ी सेनाएँ हों, अनेक प्रकार के आयुध हों तथा अन्धवी तरह से तैयारी की गई हो, क्योंकि आज आक्रमण किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और अनेक रूपों में किया जा सकता है। जब देश की सुरक्षा-सेनाएँ सशक्त एवं तैयार रहती हैं तो वे एक प्रकार से प्रतिरोधात्मक शक्ति का कार्य करती हैं। आक्रमणकारी की भाँति रक्षक को भी हथियारों, तड़नों, रणनीति एवं भूगोल के सम्बन्ध में निर्णय लेने होते हैं। इनमें से कुछ निर्णय तो आक्रमणकारी के व्यवहार द्वारा बाध्य हो कर लेने पड़ते हैं क्योंकि उसके विकल्पों को या तो सीमित या अभावहीन बनाना होता है। रक्षक को स्वतन्त्रता है कि वह युद्ध को प्रसीमित बना दे अथवा अपने कार्यों को कई प्रकार में सीमित रखे। वह केवल यह उद्देश्य बना सकता है कि आक्रमणकारी को उन सीमा तक घकेल दे जहाँ से उसने युद्ध प्रारम्भ किया था अथवा वह आक्रमणकारी को पर्याप्त मजबूती देने के उद्देश्य से उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दे। हथियार अपनाने के सम्बन्ध में रक्षक को अधिक स्वतन्त्रता नहीं होती क्योंकि उसे उन हथियारों का प्रयोग करना होता है जिनमें शत्रुओं के आक्रमण को प्रभावहीन बनाया जा सके।

एक विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा मूल रूप में सैनिक शक्ति का निष्क्रिय प्रयोग है। जब सुरक्षा के लिए योजना बनायी जाती है तो दूसरे राष्ट्रों की सामर्थ्य तथा तड़नों के सम्बन्ध में अनुमान लगाए जा सकते हैं। रक्षक द्वारा जो सैनिक शक्ति संगठित की जाती है तथा कायम रखी जाती है वह रक्षक के उद्देश्यों की अपेक्षा सम्भावित आक्रमणकारी के कार्यों पर निर्भर करती है। कुछ सैनिक पर्यवेक्षकों का तर्क है कि सुरक्षा-योजना दूसरे राष्ट्रों की सामर्थ्य पर आधारित होनी चाहिए। अन्य लोगों का कहना है कि प्रत्येक शत्रु की सामर्थ्य के विरुद्ध सुरक्षा-योजना नहीं बनायी जा सकती। आक्रमणकारी के अभिप्रायों की देख कर ही सुरक्षा का स्तर तय करना होता है। सुरक्षा में होने वाला व्यय भी एक निर्णयकारी तत्त्व होता है। रक्षात्मक

प्रयासों का रूप आक्रामक भी हो सकता है क्योंकि आक्रमणकारी के प्रयासों को शिथिल करने के लिए उसकी स्वयं की रक्षा को चुनौती देना जरूरी हो जाता है। सुरक्षा के लिए नियोजन एक बड़ा ही जटिल विषय है जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हैं।

3 प्रतिरोध की क्षमता (Deterrent Capability)—विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग प्रतिरोधात्मक रूप में भी किया जा सकता है। शक्ति के प्रयोग का यह प्रतिरोधात्मक रूप सुरक्षात्मक योजना से भी अधिक भिन्न नहीं है। एक सफल सुरक्षात्मक योजना में प्रतिरोधात्मक शक्ति का होना परमावश्यक है। जब आक्रमणकारी के विरुद्ध सुरक्षात्मक तैयारी में सैनिक शक्ति की वृद्धि की जाती है तो इसके प्रतिक्रियास्वरूप आक्रमणकारी भी अपनी शक्ति को बढ़ाता है और इस दौड़ में सीमा-रेखा कहाँ आएगी यह निश्चित नहीं रहता। वैसे एक बड़े आकार की सेना में सदैव ही एक प्रतिरोधात्मक शक्ति रहती है। आज प्रतिरोधात्मक शक्ति का महत्त्व अधिक हो गया है। एक सफल प्रतिरोधात्मक शक्ति की कुछ आवश्यकताएँ होती हैं। प्रथम आवश्यकता यह है कि रक्षक के पास इतनी पर्याप्त सेना हो कि वह सम्भावित शत्रु के किसी भी प्रकार के आक्रमण का सामना कर सके। दूसरे, प्रोत्साहित किए जाने पर रक्षक को उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरे, सम्भावित आक्रान्ता को रक्षक की सामर्थ्य को थोड़ा-बहुत अनुमान रहना चाहिए। उसे रक्षक के अभिप्रायों का भी भान रहना चाहिए। यह बात उम परम्परागत मिथ्यान्त के विरुद्ध है जिसके अनुसार सेना सम्बन्धी प्रत्येक जानकारी को शत्रु के हाथों में जाने से रोका जाता था। चौथे, रक्षक को आक्रान्ता के मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। पाँचवें, सम्भावित आक्रान्ता बुद्धिमान होना चाहिए।

इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त यह बात भी महत्त्व रखती है कि उम आक्रमण का प्रकार क्या है जिसका प्रतिरोध किया जाना है और क्या सेना द्वारा उसका प्रतिरोध किया जा सकेगा। आक्रमण व्यापक, विध्वंसक, परम्परागत, शीतयुद्ध एवं गृह-युद्ध किसी भी रूप में हो सकता है और प्रत्येक रूप में आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए एक ही प्रकार की शक्ति अपर्याप्त रहती है। आजकल विध्वंसक शस्त्रों के प्रतिरोध की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद व्यापक संहारक अथवा परम्परागत शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया है तथापि व्यापक संहार के शस्त्रों के विकास को एक मूल सैनिक आवश्यकता समझा जाता है।

व्यापक संहार के शस्त्रों द्वारा आक्रान्ता को व्यापक संहारक युद्ध करने में अथवा परम्परागत युद्ध छेड़ने से रोका जा सकता है, किन्तु ये निश्चय ही शीतयुद्ध एवं गृह-युद्ध जैसे आक्रमणों में प्रतिरोध का काम नहीं कर सकते। इन आक्रमणों का विरोध करने के लिए अन्य साधनों एवं तरीकों से युक्त परम्परागत हथियारों की आवश्यकता है।

6. छापामार क्षमता (Guerrilla Capability)—छापामार तकनीक को सैनिक शक्ति की किमी भी माना के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्रराष्ट्रों को छापामार विरोधी तकनीकों का बहुत कम ज्ञान था। कोरिया के संघर्ष के समय संयुक्तराष्ट्र संघ की फौजों ने छापामार युद्ध का प्रतिरोध करने की कुछ तकनीकों को सीखा। जब कोरिया में साम्यवादी देशों द्वारा पश्चिम का विरोध किया गया तो उन्हें छापामार युद्ध के प्रतिरोध का अनुभव हुआ। साम्यवादियों को युद्ध के इस तरीके का महत्त्व ज्ञात है तथा वे इसका हर जगह प्रयोग करते हैं। माओत्से तुंग को छापामार युद्ध के प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में याद किया जाता है। विषयनाम युद्ध छापामार तड़ाई में साम्यवादियों की उत्कृष्टता का परिचायक था।

युद्ध को रोकने का प्रयास

(Preventive and Detective Measures)

अमेरिका के राज्य-सचिव (Secretary of State) जॉन फास्टर डलेस (John Foster Dulles) द्वारा युद्ध को रोकने के लिए समय-समय पर दिए गए सुझावों की निम्नलिखित सूची पेश की गई थी—

- (1) युद्ध के भयावह परिणामों की शिक्षा देना
(Education as to the fact Horrors of War)
- (2) 'युद्ध से कोई लाभ नहीं होता' इस बात की शिक्षा देना
(Education to the fact that 'War does not pay')
- (3) अलगवट और आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीयवाद
(Isolation and Economic Internationalism)
- (4) कैलागब्रिअंड सन्धि या पेरिस की सन्धि
(The Pact of Paris Vs Kellogg-Briand Pact)
- (5) राष्ट्रसंघ (League of Nations)
- (6) आक्रमण से प्राप्त होने वाले लाभों को मान्यता प्रदान न करना
(Non-recognition of the Fruits of Aggression)
- (7) शस्त्रीकरण (Armament)
- (8) निःशस्त्रीकरण (Disarmament)
- (9) अनुमति या दबाव (Sanctions)

युद्ध को रोकने तथा शान्ति की स्थापना करने के उक्त सभी प्रयासों को डलेस (Dulles) ने असत्य तथा अपर्याप्त समाधान (False and Inadequate Solutions) कहा था। उन्होंने इन सभी सुझावों का क्रमशः परीक्षण किया और पाया कि इनके द्वारा विश्व-शान्ति प्राप्त नहीं की जा सकती; ये वृथा हैं। पामर तक पकिस के मतानुसार डलेस ने इन सुझावों पर जो विचार-विमर्श किया वह मुख्य रूप से सैद्धान्तिक (Theoretical or Academic) है। डलेस (Dulles)

द्वारा दी गई सूची में अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा विश्व-सरकार का उल्लेख नहीं है। वैसे कई विचारकों ने इन दोनों ही साधनों द्वारा विश्व-शान्ति की स्थापना की सम्भावना पर जोर दिया है। किन्तु पामर तथा पार्किंस ने इन दोनों सुझावों पर विचार करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि युद्ध के विकल्प (Alternative) के रूप में दोनों ही सुझाव अपूर्ण तथा असन्तोषजनक हैं। आज के अणु-युग में युद्धों को रोकने का प्रयास करना परम आवश्यक बन गया है। राष्ट्रपति अय्यूब से वार्ता के लिए ताशकन्द जाने से एक दिन पूर्व (2 जनवरी, 1966) प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा था कि यदि हरेक समस्या का हल करने के लिए शस्त्रों का प्रयोग किया गया तो विश्व में शान्ति नहीं रह सकती। सभी देशों को अपने आपसी विवाद शान्तिपूर्ण वार्ताओं द्वारा तय करने चाहिए। युद्ध का विकल्प ढूँढना आज के युग की प्रमुख आवश्यकता बन गया है, किन्तु युद्ध के केवल वही विकल्प कारगर हो सकते हैं जो यौद्धिक सुरक्षा-कार्यों को नियन्त्रित कर सकें तथा जो बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शान्ति स्थापित रखने के लिए प्रयुक्त किए जाएँ।



राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ : शक्ति-सन्तुलन, सामूहिक सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान

(Limitations of National Power : Balance of
Power, Collective Security and Pacific
Settlement of International Disputes)

“शक्ति-सन्तुलन व्यक्तियों और समुदायों की सापेक्षिक शक्ति की घोर संकेत करता है।” —श्लीजर

स्वतन्त्र और सम्प्रभु राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् की प्राथमिक इकाइयाँ हैं। ये सभी राज्य राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर पारस्परिक व्यवहार करते हैं और अपने हितों की सिद्धि के लिए शक्ति (Power) का प्रयोग करते हैं, तथापि वे गनमानी करने के लिए एकदम स्वतन्त्र नहीं होते क्योंकि विभिन्न कारणोंवश उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का सम्मान करना पड़ता है और वे अपनी प्रभुसत्ता तथा शक्ति-प्रयोग के निरंकुश प्रयोग में विवशता अनुभव करते हैं। ये अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीय शक्ति तथा प्रभुसत्ता के निर्बोध प्रयोग पर नियन्त्रक का कार्य करती हैं। राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने वाली प्रमुख सीमाएँ ये हो सकती हैं—

1. शक्ति-सन्तुलन,
2. सामूहिक सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान,
3. अन्तर्राष्ट्रीय कानून,
4. विश्व-सरकार,
5. निःशस्त्रीकरण,
6. अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता,
7. विश्व-जनमत।

प्रस्तुत अध्याय में प्रथम दो सीमाओं का विस्तार से विवेचन किया जाएगा।

शक्ति-सन्तुलन (Balance of Power)

आधुनिक विचारकों ने शक्ति-सन्तुलन को 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार-

भूत सिद्धान्त'¹ (A Basic Principle of International Relations), 'सामान्य सामाजिक सिद्धान्त की अभिव्यक्ति'² (A Manifestation of General Social Principle), तथा 'राजनीति का यथासम्भव मूलभूत नियम'³ (A Nearly Fundamental Law of Politics as it is Possible to Find) आदि की संज्ञा दी है। शक्ति-सन्तुलन की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिज्ञों की व्यावहारिक नीतियों का विवेचन किया गया है। यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हमेशा अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन को बनाने, बनाए रखने और उसकी रक्षा करने में सलग्न रहते हैं। आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा कायम रखने के एक बहुमूल्य यन्त्र के रूप में शक्ति-सन्तुलन ने अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है।

शक्ति-सन्तुलन की परिभाषाएँ (Definitions of Balance of Power)

शक्ति-सन्तुलन-सिद्धान्त की परिभाषाएँ इतने रूपों में दी गई हैं कि यह सिद्धान्त अस्पष्टता से व्याप्त है। सामान्यतः शक्ति-सन्तुलन का अर्थ प्रायः राष्ट्रों के बीच शक्ति के सामान्य वितरण से लिया जाता है और कभी-कभी स्थिति विशेष में इसका अभिप्राय एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र पर छा जाने से होता है। यहाँ प्रमुख विचारकों की शक्ति-सन्तुलन सम्बन्धी परिभाषाएँ प्रस्तुत की जाती हैं और तब अगले शीर्षक के अन्तर्गत पृथक् से शक्ति-सन्तुलन के अनेक अर्थों और प्रयोगों की व्याख्या की जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सुविख्यात विचारक हेस जे.मॉर्गेन्थो (Morgenthau) के मतानुसार 'प्रत्येक राष्ट्र यथा-स्थिति (Status-quo) को बनाए रखने अथवा परिवर्तित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है।' इसके परिणामस्वरूप जिस ढाँचे (Configuration) की आवश्यकता होती है वह शक्ति-सन्तुलन कहलाता है और जिन नीतियों की आवश्यकता होती है उनका सक्षम शक्ति-सन्तुलन को बनाए रखना होता है। श्लीचर (Schleicher) के अनुसार "शक्ति-सन्तुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की घोर संवेत करता है।" क्लॉड (I L Claude) ने शक्ति-सन्तुलन को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति-सम्बन्धों की समस्या से सम्बन्धित माना है। उनका कहना है कि "शक्ति-सन्तुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतन्त्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति-सम्बन्धों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतन्त्रापूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था (Decentralized System) है जिसमें शक्ति व नीति-निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है।" प्रो. फे (Prof. Fay) के शब्दों में, "शक्ति-सन्तुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति न्यायपूर्ण तुल्यभारिता

1 Palmer and Perkins : op. cit., p. 212.

2 Morgenthau : op. cit., p. 161.

3 Martin Wright : Power Politics, pp. 45-46.

(Just Equilibrium) जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने से रोक सके।" बिक्सन के मत में 'सन्तुलन' (Balance) शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों ही अर्थों में किया जाता है। लेखा (Account) सन्तुलन का अर्थ होता है समानता, किन्तु जब सन्तुलन किसी एक के हित में हो तो इसका अर्थ होता है असमानता। उनका कहना है कि शक्ति-सन्तुलन का सिद्धान्त प्रथम अर्थ का दावा करता है, किन्तु दूसरे के लिए प्रयत्नशील रहता है। मॉर्गेन्थो भी 'शक्ति-सन्तुलन' शब्द का अर्थ 'राष्ट्रों के मध्य स्थित शक्ति की समानता' से मानते हैं, किन्तु यह तभी सम्भव है जब शक्ति शब्द के साथ कोई विश्लेषण न प्रयुक्त किया गया हो। इसके विपरीत स्पाइकमेन (Spykman) के कथनानुसार, "सच्चाई यह है कि प्रत्येक देश केवल उसी शक्ति-सन्तुलन में रुचि लेता है जो उसके हित में होता है।" इस प्रकार जो राष्ट्र शक्ति-सन्तुलन की स्थापना करना चाहता है वह 'सन्तुलन' नहीं बरन् अपने हित में असन्तुलन (Imbalance) की स्थापना का प्रयत्न करता है।

पामर तथा पॉक्स ने शक्ति-सन्तुलन की माध्यता की निम्नलिखित सात विशेषताओं का उल्लेख किया है—

1. विश्व के राष्ट्रों के बीच शक्ति-सन्तुलन सदैव बना नहीं रह सकता;
2. शक्ति-सन्तुलन की स्थापना स्वतः ही नहीं हो जाती, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है;
3. शक्ति-सन्तुलन का मापदण्ड युद्ध है, क्योंकि युद्ध प्रायः तभी आरम्भ होते हैं जबकि शक्ति-सन्तुलन विच्छिन्न हो जाता है;
4. शक्ति-सन्तुलन की नीति गतिशील (Dynamic) एवं परिवर्तनशील (Changing) होती है;
5. इतिहासकार शक्ति-सन्तुलन को वस्तुनिष्ठ (Objective) दृष्टि से देखता है किन्तु राजनीतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) दृष्टि से देखता है;
6. शक्ति-सन्तुलन न तो प्रजातन्त्रात्मक देशों के लिए ही उपयुक्त है और न तानाशाही देशों के लिए ही;
7. शक्ति-सन्तुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही सिलायी होते हैं, छोटे राष्ट्र केवल प्रभावित (Victim) या दर्गदर के रूप में रहते हैं। किन्तु यदि वे आपस में मिल जाएँ तो इस खेल में सक्रिय हिस्सेदार भी बन सकते हैं।

अवधारणा का इतिहास (The History of Concept)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति-सन्तुलन की अवधारणा का इतिहास पर्याप्त पुराना है। राज्यों के बीच सम्बन्धों में बहुत पहले से ही संघर्ष, मतभेद, विरोध एवं युद्ध रहे हैं। इनका निपटारा करने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था करने की प्रयत्ना प्रारम्भ में एक या एक से अधिक राज्य अनेक राज्यों पर प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा करते थे और फिर विश्व को अपनी अवधारणा के अनुसार रूप प्रदान करने का प्रयास करते थे। दूसरे राज्यों द्वारा स्थिति को यथास्थित रखने की चेष्टा की जाती थी और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अपने विभिन्न सोपानों में गुजरती हुई आगे बढ़ती

रहती थी। जब विरोधी राज्य कुछ राज्यों के सामान्य हितों को चुनौती देते थे तो वे मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए सन्धि-बद्ध हो जाते थे। शक्ति-सन्तुलन की प्रक्रिया एक प्रकार से दूसरे राज्यों के शक्ति-प्रयोग को सीमित कहने का प्रयास है।

शक्ति-सन्तुलन की तुल्यभारिता का विचार मूल रूप से प्रकृति की विरोधी शक्तियों के बीच स्वाभाविक तुल्यभारिता से लिया गया। मनुष्य ने बहुत पहले से ही इस बात की अनुभूति की कि सारे सौरमण्डल में अनेक नक्षत्र और ग्रह किस प्रकार सन्तुलन बनाए रखते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अरस्तू ने यह विचार प्रकट किया कि समाज गरीब, निर्धन और मध्यवर्ग के लोगों के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप सन्तुलन बनाए रखते हैं। एक अन्य राजनीतिक विचार जेम्स मैडिसन (James Madison) का विश्वास था कि सरकार को उन तत्त्वों के बीच सन्तुलन बनाए रखना चाहिए जो परिवर्तन चाहते हैं और जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। राजनीतिक विचारको ने बहुत पहले से ही शक्ति-सन्तुलन पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ये विचार सही थे अथवा नहीं, यह अलग बात है, किन्तु अपने समय में ये पर्याप्त प्रभावशील रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति-सन्तुलन को पूर्ण शक्ति एवं तानाशाही को दबाए रखने के साधन के रूप में देखा गया है। डेविड ह्यूम (David Hume) ने अपने निबन्ध 'शक्ति-सन्तुलन पर' (On the Balance of Power) में पोलिटियस (Politics) को उद्धृत किया है जिसका कहना था कि किसी भी राज्य या शासक को इतना महान् न बनने दो कि वह अपने पड़ोसी को उसके अधिकारों की रक्षा में असमर्थ बना दे। मैकियावेली ने अपनी रचना 'द प्रिन्स' (The Prince) में यह परामर्श दिया है कि जो भी दूसरे की शक्ति को बढ़ाने में योगदान देता है वह अपनी शक्ति को नष्ट करता है। रिचार्ड कोब्डन (Richard Cobden) ने शक्ति-सन्तुलन को एक असम्भव कल्पना के रूप में विशिष्टता प्रदान की है। ये और कुछ नहीं केवल शब्द मात्र हैं। उनके मतानुसार शक्ति-सन्तुलन केवल मस्तिष्क को स्पर्श करता करता है, विचारों को नहीं। हमारे पूर्वजों ने उन शब्दों के सम्बन्ध में अपने आप को परेशान करने की ओर नोचि अपनाई थी यह उसी का एक उदाहरण है। फ्रांसीसी दार्शनिक फेनेलोन (Fenelon) इस मान्यता को पर्याप्त महत्त्व देते हैं। उनके कथनानुसार अपने पड़ोसी को बहुत अधिक शक्तिशाली बनने से रोकना अपने आपको तथा अन्य पड़ोसियों को गुलाम बनने से रोकने का प्रयास है। यह स्वतन्त्रता, समानता एवं सुरक्षा की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि एक देश की प्रतिशय शक्ति एक सीमा से बाहर निकलने के बाद सम्बद्ध राज्यों की सामान्य व्यवस्था को परिवर्तित कर देती है। लिओपोल्ड वॉन रॉन्के (Leopold Von Ranke) का मत है कि यूरोपीय राजनीति में एक ओर तो दबाव डाले जाते थे और दूसरी ओर उनका विरोध किया जाता था। इस व्यवस्था के कारण ही यूरोप अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सका तथा अपने प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता की रक्षा कर सका था तथा अपने प्रत्येक राज्य का स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रख सका। ऐसा ही कुछ मन एडवर्ड गिग्न (Edward

Gibbon) ने प्रकट किया है। उनका कहना है कि यूरोप का अनेक स्वतन्त्र राज्यों में विभाजन होना अनेक लाभदायक परिणामों का जनक रहा है। इससे मानव-जाति की स्वतन्त्रता कायम रही। जिस तानाशाह को अपनी जनता के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता उसे अपने समकक्ष राजाओं की शक्ति का प्रभाव शीघ्र ही ज्ञात हो जाता है। उसे अपने मित्रों की सलाह और शत्रुओं की चुनौतियों से मर्मादित होना पड़ता है।”

सन् 1815 में जैफरसन (Jeffarson) ने अपने एक मित्र को लिखा या कि इस बात में हमारा हित नहीं है कि समस्त यूरोप एक राजतन्त्र के रूप में संगठित हो जाए। उसने आशा की कि राष्ट्रों के बीच एक उपयुक्त शक्ति-सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए। संयुक्तराज्य अमेरिका ने अपने प्राप को यूरोपीय व्यवस्था से पृथक् रखा, किन्तु जब सन् 1917 और सन् 1941 में उसे सन्तुलन की स्थापना के लिए आमन्त्रित किया गया तो वह मना नहीं कर सका। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट से बात करने के बाद सन् 1944 में फारेस्ट डेविस (Forest Davis) ने बताया कि इंग्लैंड की भाँति हमारा ऐतिहासिक स्तर भी यह माँग करता है कि यूरोप में शक्ति-सन्तुलन की स्थापना रहे और कोई भी एक राष्ट्र इस महाद्वीप के साधन-स्रोतों तथा मानव-शक्ति को हमारी सम्भावित हानि के लिए प्रयुक्त न करे। इस मूल बात से प्रभावित होकर ही सन् 1971 में लड़े थे और इसीलिए अब लड़ रहे हैं, ताकि किसी एक आक्रमणकारी शक्ति को यूरोप पर स्वामित्व रखने से रोका जा सके। पर्ल हार्बर (Pearl Harbour) से लेकर अब तक संयुक्तराज्य अमेरिका यूरोपीय तथा विश्व रंगमंच को इसी दृष्टि से देख रहा है।

शक्ति-सन्तुलन या तुल्यभारिता की मान्यता अनेक संधियों का आधार मानी जाती है। सन् 1648 में सन् 1914 तक का काल स्पष्टतः शक्ति-सन्तुलन का काल कहलाता है। कहा जाता है कि सन् 1648 की वेस्टफालिया की सन्धि (The Treaty of West Phalia), सन् 1815 का वियना समझौता (Vienna Settlement), सन् 1919 की वर्साय सन्धि (The Treaty of Versaillis) तथा सन् 1945 में संयुक्तराष्ट्रसंघ की स्थापना के पीछे शक्ति-सन्तुलन की धारणा कार्य कर रही थी। ये विभिन्न सन्धियाँ एवं समझौते इसलिए हुए क्योंकि समय-समय पर नेपोलियन, कैसर विल्हेम (Kaiser Wilhem), हिटलर और साम्यवादी नेताओं ने विश्व पर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास किया। शक्ति-सन्तुलन की अवधारणा में विरोधाभास यह है कि जो देश इसका व्यवहार करते हैं वे भी यह घोषणा नहीं करना चाहते कि वे इसका व्यवहार कर रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी देश शक्ति-सन्तुलन को अपनी नीति मानने का दावा नहीं करता। वे राजनीति की इस प्रकार की व्यवस्था में सम्मिलित होने से मना करते हैं यद्यपि उनकी नीतियाँ दूसरे राज्यों की शक्तियों को दबाने, विरोध करने, कम करने तथा उनसे आगे बढ़ने की ओर संचालित रहती हैं। शक्ति-सन्तुलन की नीति की राष्ट्रीय सद्य के रूप में घोषणा दूसरे देशों को विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। आक्रमणकारी देश ऐसी स्थिति में

अपने आपको मंगठित तथा मशक्त बनाने के प्रयासों को न्यायोचित ठहरा सकता है उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक मान सकता है।

शक्ति-सन्तुलन की तीन अभिधारणाएँ

(Three Postulates of Balance of Power)

शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त की कुछ अभिधारणाएँ हैं। उनमें से तीन यहाँ उल्लेखनीय हैं—

1 प्रथम यह कि एक राज्य को परिस्थितियों के बदलने पर तथा नई घमकियों के आने पर अपनी सन्धियों में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिद्धान्त सम्बन्धी दुराग्रह एवं वचनबद्धता शक्ति-सन्तुलन में कठोरता एवं अपरिवर्तन-शीलता उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए शक्ति-सन्तुलन की राजनीति इनकी अवहेलना करती है। किन्तु यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि साम्यवादीयों ने दूसरे राज्यों पर अपनी विचारधारा को थोप दिया है इसीलिए विचारधारा सम्बन्धी संघर्ष वर्तमान विश्व-राजनीति की एक प्रमुख वास्तविकता बन गया है। शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था के समर्थकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को न्यूनतम कर दिया जाता है, क्योंकि ये राजनीतिज्ञों की राष्ट्रीय हितों की साधना के लिए शक्ति की दृष्टि से सोचने से रोक देते हैं। एक देश किसी भी सन्धि के अनुसार वचनबद्ध हो सकता है, किन्तु परिस्थितियाँ बदलने पर वह वचनबद्धता टूट सकती है। उदाहरण के लिए ग्रेट-ब्रिटेन प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जापान के साथ सन्धि द्वारा वचनबद्ध था, किन्तु जब उसने सयुक्तराज्य अमेरिका के साथ अपना सहयोग बढ़ा लिया तो इस सन्धि को तोड़ना आवश्यक हो गया। इस प्रकार राज्यों को अपने हितों तथा सम्बन्धों का पुनर्वीक्षण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्रान्स के राष्ट्रपति जनरल डिगान ने नाटो सन्धि के सम्बन्ध में ऐसा ही किया है। इस दृष्टि से यह भी सम्भावना है कि यदि इन देशों के राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से आवश्यकता हुई तो सयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत संघ साम्यवादी चीन का विरोध करने में उसी प्रकार मिल जायेंगे जैसे वे जर्मनी का विरोध करने में मिले थे। इतिहास में अचानक ही बड़े-बड़े परिवर्तन हो जाते हैं जिनकी हम पहले से कल्पना नहीं कर सकते थे। जिम जापान के विरुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध में सयुक्तराज्य अमेरिका ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी वह अब इनका परम मित्र है।

2. दूसरी अभिधारणा यह है कि जब राज्यों को यह ज्ञान हो कि दूसरे राज्य शक्ति-सन्तुलन को उसके मुख्य हितों के विरुद्ध परिवर्तित कर रहे हैं तो उसे संघर्ष के लिए और यहाँ तक कि आवश्यकता हो तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्यूबा के प्रश्न पर सयुक्तराज्य अमेरिका का दृष्टिकोण इस का चोकर है। जब सोवियत-संघ क्यूबा में बड़े स्तर पर प्रश्लेषाम्त्र स्थापित करने जा रहा था राष्ट्रपति कनेडी ने 22 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी जनता और प्रधानमंत्री मन्शेवर को कहा कि “सोवियत भूमि के बाहर रणनीक्षण के हथियार स्थापित करने का यह आक्रमिक प्रथम निर्णय यथास्थिति में जानबूझ कर किया गया आक्रमणकारी एवं अन्यायपूर्ण परिवर्तन है जिसकी हम देश द्वारा स्वीकार नहीं

किया जा सकता वरना इस देश के शत्रु और मित्र इसके साहस और वचनों में कभी दुबारा विश्वास नहीं करेंगे।" इतने पर भी जब चुनौती सामने आ गई तो राष्ट्रपति ने कहा कि "हम प्रतावश्यक रूप से अथवा बिना सोचे समझे विश्वव्यापी अणुयुद्ध की जोखिम नहीं लेते जिसमें विजय के फलस्वरूप हमारे लिए केवल राख बचेगी; किन्तु यदि हमें इस जोखिम में पड़ने को बाध्य किया गया तो किसी भी समय उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।"

3 तीसरी अभिपारणा उपर्युक्त दोनों से ही सम्बद्ध है तथा उन्हीं से उद्भूत है। इसके अनुसार यदि युद्ध या अन्य सकट उत्पन्न होता है तो उसमें किसी भी देश का इतना अधिक बिनाश नहीं किया जाना चाहिए कि सम्बन्ध शक्तियाँ अकेली पड़ जाएँ और विजेता के लिए अनुपयुक्त शक्ति-सन्तुलन की स्थिति उत्पन्न कर दें। ऐसा सन् 1945 में जर्मनी के साथ किया गया। उनका पूरी तरह से बिनाश कर दिया गया और इस प्रकार इटली और जापान की शक्ति कमजोर हो गई। इसकी पाँच वर्ष में ही पश्चिमी शक्तियों को यूरोप और एशिया में साम्यवादी चुनौती के विरुद्ध शक्ति-सन्तुलन कायम रखने के लिए इन तीनों पूर्व शत्रु-शक्तियों की सहायता करना जरूरी हो गया।

शक्ति-सन्तुलन का मूल तत्त्व लॉर्ड पामर्स्टन (Lord Palmerston) ने प्रामिष्यक्त किया है। उनके कथनानुसार, "इंग्लैंड का कोई अन्तरंग मित्र नहीं है और न ही कोई अन्तरंग शत्रु है वरन् उसके तो अन्तरंग हित हैं।" प्रोफेसर निकोलस स्पाइकमैन ने भी कुछ इसी प्रकार के भावों को अन्य शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उनका कहना है कि "जो राज्य शक्ति-सन्तुलन का खेल खेलता है उसका कोई स्थायी मित्र नहीं हो सकता। उसका सहयोग किसी एक राज्य के प्रति नहीं हो सकता वरन् केवल सन्तुलित शक्ति के प्रति होगा। घाज के मित्र आने वाले कल के शत्रु हो सकते हैं।" स्पाइकमैन ने आगे बताया है कि शक्ति-राजनीति का एक मुख्य आकर्षण यह है कि यह एक राज्य के मित्रों को क्षुब्ध होने का अवसर नहीं देती। यदि हम सन् 1930 तथा उसके बाद होने वाली सन्धियों तथा सहयोगों पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था हमें इस बात का आश्वासन देती है कि कोई भी विरोधी हमेशा के लिए विरोधी नहीं बनता क्योंकि वह अवसर और परिस्थितियों के बदलते ही पुनः मित्रता का हाथ बढ़ा देता है।

शक्ति-सन्तुलन की अस्पष्टता के अनेक अर्थ
(Balance of Power as an Ambiguous Concept)

मार्टिन वाइट (Martin Wight) के अनुसार, "एक इतिहासकार शक्ति-सन्तुलन तब मानता है जब विरोधी समुदाय की शक्ति उसके बराबर होती है, किन्तु एक राजनीतिज्ञ के मतानुसार शक्ति-सन्तुलन तब होगा जबकि उनका पक्ष दूसरे की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होगा और जबकि उसके देश को राष्ट्रीय हित के अनुसार चाहे जिस पक्ष में मिलने की स्वतन्त्रता होगी।"

क्लाड (I. L. Claude) का कथन है कि शक्ति-सन्तुलन शब्द का प्रयोग मुख्यतः निम्न रूपों में किया जा सकता है—

1. एक अवस्था के रूप में (As a Situation)—क्लाड के अनुसार शक्ति-सन्तुलन का प्रयोग कभी तो तुल्यभारिता (Equilibrium) के लिए किया जाता है और कभी इसे तुल्यभारिता के विरोधी अर्थ (Disequilibrium) में किया जाता है। इस दृष्टि से शक्ति-सन्तुलन 'शक्ति-वितरण' का समानार्थक बन जाता है जिस प्रकार कि 'तापमान' जलवायु की स्थिति को बताता है चाहे वह गर्म हो या ठण्डा, इसी प्रकार शक्ति-सन्तुलन भी 'शक्ति-स्थिति' को बताता है चाहे वह सन्तुलित हो अथवा असन्तुलित।

2. नीति के रूप में (As a Policy)—शक्ति-सन्तुलन शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसी नीति के रूप में भी किया जा सकता है जो तुल्यभारिता का निर्माण करने अथवा उसकी रक्षा करने का कार्य करती हो। यह नीति इस धारणा पर आधारित रहती है कि असन्तुलित शक्ति खतरनाक होती है। जब चर्चिल (Winston Churchill) ने यह लिखा कि शक्ति-सन्तुलन ब्रिटिश नीति की आश्चर्यजनक अनभिप्रेत परम्परा (Unconscious Tradition) रही है तब उनका अर्थ सन्तुलन की स्थिति से नहीं बरन् सन्तुलन करने वाली नीति से था। मोवर (Mowrer) ने शक्ति-सन्तुलन का जो रूप बताया है उससे भी शक्ति-सन्तुलन का अर्थ एक ऐसी नीति से लगाया जा सकता है जो कार्यों के बीच तुल्यभारिता (Equilibrium) लाने में प्रयत्नशील हो। इस प्रकार शक्ति-सन्तुलन शब्द का प्रयोग प्रायः शक्ति-स्थिति से सन्निय रूप से सम्बन्धित रहता है। मॉर्गन्थो और थॉम्पसन ने भी शक्ति-सन्तुलन का प्रयोग नीति के रूप में ही किया है क्योंकि वे मानते हैं कि "शक्ति-सन्तुलन एक देश के उन प्रयत्नों को कहते हैं जिन्हें वह दूसरे देश के विरुद्ध अपनी शक्ति को इतनी बढ़ाने के लिए करता है जिससे वह दूसरे देश से यदि अधिक नहीं तो कम से कम बराबर तो हो जाए।"

3. व्यवस्था के रूप में (As a System)—प्रायः शक्ति-सन्तुलन का प्रयोग अनेक राज्यों से पूर्ण इस विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को त्रियान्वित करने की एक व्यवस्था के रूप में भी कर दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों में शक्ति-सन्तुलन-व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। टेलर (Taylor) ने शक्ति-सन्तुलन का प्रयोग राज्यों के परस्पर सम्बन्धों के रूप में किया है।

4. प्रतीक के रूप में (As a Symbol)—अनेक विचारकों ने शक्ति-सन्तुलन शब्द का प्रयोग किसी पारिभाषिक अर्थ में न कर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति की समस्या के यथार्थवादी तथा दूरदर्शी प्रतीक (Symbol) के रूप में किया है। इन विचारकों के मतानुसार शक्ति-सन्तुलन की नीति के अभाव का अर्थ है सैनिक कमजोरी, मित्रों का अभाव तथा आक्रमणकारी की शक्ति को सन्तुलित करने

के प्रयत्नों का प्रभाव।¹ बुधरो विल्सन की नीति की आलोचना प्रायः इसी आधार पर की जाती है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की एक तथ्य के रूप में देखने से मना कर दिया तथा एक आशावादी के मस्तिष्क से काम लेते हुए अन्तर्राष्ट्रीयवाद पर ही विचार करता रहा। इस सबका अर्थ यही होता है कि शक्ति सन्तुलन को यथार्थवाद का प्रतीक माना जाने लगा है और इसीलिए राजनीतिज्ञों एवं विचारकों से आशा की जाती है कि वे इसका आदर करेंगे।

मि. ई. हैस (Mr Ernst Hass) ने शक्ति-सन्तुलन शब्द का प्रयोग करने वाले विचारकों के अर्थ एवं अभिप्राय का वर्णन किया है। मि. हैस के कथनानुसार कुछ लोग शक्ति-सन्तुलन को व्याख्या के रूप में (As Description) प्रयुक्त करते हैं। ये विचारक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को किसी भी सैद्धान्तिक या विरलेपणात्मक उद्देश्य के लिए समझने से पूर्व शक्ति-सन्तुलन को समझना आवश्यक मानते हैं। वर्तमान समय में पत्र-सम्पादकों एवं रेडियो के आलोचकों द्वारा इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है। जब श्रोतागण इस शब्द को सुनते हैं तो वे इसका अर्थ केवल शक्ति का वितरण ही खगाते हैं, न कि सन्तुलन। दूसरे अवसरों पर शक्ति-सन्तुलन का अर्थ शक्ति के वितरण से कुछ अधिक होता है। यहाँ इसका अर्थ तुल्यभारिता या प्रभुत्व या महत्त्व से हो सकता है। यहाँ एक बात यह उल्लेखनीय है कि इस शब्द का प्रयोग करने वाले के अभिप्राय भी शब्द के अर्थ पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक लेखक अपने उद्देश्य के अनुसार ही एक कार्य को शक्ति-सन्तुलन का स्थापक मानता है जबकि दूसरा अपने उद्देश्य की दृष्टि से उसके विपरीत कार्य को ऐसा मान सकता है। पिछली शताब्दी में फ्रांसीसी लेखकों ने तुल्यभारिता (Equilibrium) शब्द का प्रयोग आस्ट्रिया पर युद्ध की माँग का समर्थन करने के लिए किया था। सात वर्ष तक यह युद्ध चला, किन्तु इस काल में ब्रिटिश अधिकारी शक्ति-सन्तुलन की नीति के आधार पर प्रुशिया (Prussia) के समर्थन को न्यायोचित ठहराने लगे, क्योंकि उनके मतानुसार फ्रेडरिक द्वितीय (Fredrick II) ने ही आस्ट्रिया पर आक्रमण करके शक्ति-सन्तुलन को बिगाड़ा था। आज भी शक्ति-सन्तुलन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह सर्वदा एक ही अर्थ में नहीं होता। वह शक्ति का वितरण तुल्यभारिता एवं प्रभावशीलता में से किसी भी अर्थ में प्रयुक्त किया जा सकता है।

शक्ति-सन्तुलन के प्रयोग का दूसरा रूप प्रचार एवं विचारधारा (Propaganda and Ideology) का है। जब सन्तुलन का अर्थ शान्ति अथवा युद्ध के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे समझना सहज बन जाता है। जब हम सन्तुलन शब्द का प्रयोग शान्ति की स्थापना एवं खतरे के लिए तथा युद्ध को छोड़ने एवं रोकने के लिए कर सकते हैं तो यह स्पष्ट है कि सन्तुलन जैसी कोई चीज 'सन्तुलन' (अर्थात् शान्ति एवं युद्ध) के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ सन्तुलन शब्द का प्रयोग बिना किसी निश्चित अर्थ के केवल प्रचार के लिए किया जाता है। शक्ति-सन्तुलन

शब्द का प्रयोग करके एक राज्य अपनी नीतियों को यथास्थित रूप में ही न्यायोचित सिद्ध करना चाहता है। कुछ उदाहरणों में इस शब्द का प्रयोग सैद्धान्तिक मतभेदों के रूप में किया गया तथा कुछ उदाहरणों में हारे हुए राज्य की शक्ति एवं आकार को न्यायोचित बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस प्रकार इस शब्द के प्रयोग का अर्थ यह नहीं है कि प्रयोगकर्त्ता किसी निश्चित सिद्धान्त में विश्वास करता है वरन् यह है कि वह इसे अपने हितों की प्राप्ति में उपयोगी मानता है।

प्रचार की दृष्टि से जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो तथ्यों का प्रयोग बेईमानी के साथ किया जाता है तथा बौद्धिक रूप से स्थापित मान्यताओं को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। प्रचार तो झूठी बात का जानबूझ कर किया गया स्थापन होता है। शक्ति-सन्तुलन के द्वारा विचारधारा सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। मानहीम (Mannheim) के कथनानुसार विचारधारा कुछ प्रतीकों में विश्वास करती है चाहे वे प्रतीक वस्तुगत रूप से झूठे ही क्यों न हों। शक्ति-सन्तुलन का सहारा लेकर एक देश नीतियों को प्राकृतिक कानून के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है, नैतिक रूप से उचित सिद्ध कर सकता है अथवा इनको एक ऐतिहासिक आवश्यकता बता सकता है। इस अर्थ में जब शक्ति-सन्तुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम इसे केवल प्रचार मात्र ही नहीं कह सकते क्योंकि इस प्रकार इसे प्रयोग करने वाला अपने आपको भी धोखा देता है।

18वीं शताब्दी में शक्ति-सन्तुलन की मान्यता की आलोचना की गई। जस्टी (Justi) ने अपने एक लेख में बताया कि शक्ति-सन्तुलन का सिद्धान्त और कुछ भी नहीं, केवल विचारधारा सम्बन्धी तर्क है जो राजनीतिज्ञों द्वारा अपने असली उद्देश्यों अर्थात् आक्रमणकारी उद्देश्यों को छिपाने के लिए अपनाया जाता है। जस्टी कहते हैं कि राज्य भी व्यक्तियों की भाँति केवल अपने व्यक्तिगत हित से ही निर्देशित होते हैं। हित चाहे वास्तविक हो अथवा अवास्तविक वे शक्ति-सन्तुलन से निर्देशित नहीं होते। ऐसे किसी भी राज्य का उदाहरण नहीं दिया जा सकता जो केवल शक्ति-सन्तुलन की स्थापना के लिए ही अपने हितों के विरुद्ध अथवा किसी विशेष हित के बिना ही युद्ध में सम्मिलित हुआ हो। इस प्रकार प्रचार के लिए तथा विचारधारा के लिए शक्ति-सन्तुलन शब्द के प्रयोग में कुछ अधिक अन्तर नहीं है। जब अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच के अभिनेता यह मान ले कि शक्ति-सन्तुलन स्थापित करने की सामान्य आवश्यकता में ही उनका व्यक्तिगत हित संयुक्त है तो शक्ति-सन्तुलन का आश्रय प्रचारमात्र न रह कर विचारधारागत बन जाता है।

शक्ति-सन्तुलन शब्द के प्रयोग का तीसरा रूप विश्लेषणात्मक धारणा के रूप में है। यह रूप प्रचार के उद्देश्य से प्रयुक्त शक्ति-सन्तुलन के रूप में पूर्णतः भिन्न ही नहीं वरन् विपरीत भी होता है। इस प्रकार जब यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है तो प्रयोग करने वाला इसे अपने विश्लेषण का आधार बनाना चाहता है। इस अभिप्राय से युक्त होते-होते यह सब 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में अन्तर्राष्ट्रीय

विचारधारा के रूप में विकसित हो गया। इस रूप में प्रयुक्त होने पर भी 'शक्ति-सन्तुलन' शब्द के अनेक अर्थ लगाए गए। विद्वान्पूर्ण विश्लेषण के लिए भी इस शब्द का शक्ति-राजनीति, तुल्यभारिता, प्रभुत्व एवं विश्वव्यापी कानून आदि अर्थों में प्रयोग किया गया।

रील डी करबा (Reel de Curban) के कथनानुसार शक्ति-सन्तुलन का मूल सिद्धान्त अवरोधना है। यदि अन्तिम विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो एक शासन की शक्ति और कुछ न होकर केवल उसके पड़ोसियों की शक्तिहीनता होती है। दूसरों की शक्तिहीनता ही एक देश की शक्ति होती है। वर्तमान काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था से समानता रखती है और इस प्रकार की स्थिति में यह निष्कर्ष पर्याप्त उपयुक्त प्रतीत होता है।

शक्ति-सन्तुलन सिद्धान्त को एक विश्लेषणात्मक सिद्धान्त के रूप में प्रयुक्त करने की चेष्टा उन लेखकों द्वारा भी की गई है जो शक्ति-सन्तुलन को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मूल तत्त्व मानते हैं। इस अर्थ में सन्तुलन इतिहास का कानून बन जाता है। प्रोफेसर मॉर्गेंथौ तथा गूमी ने शक्ति-सन्तुलन को व्यापक अर्थ प्रदान किया है। वे इसे केवल तुल्यभारिता एवं प्रभुत्वशीलता मान ही नहीं मानते। इन लेखकों का मत है कि 'शक्ति-सन्तुलन' सम्प्रमुता पर आधारित बहुराज्य व्यवस्था में निहित रहता है। वे राज्य किसी भी लक्ष्य के लिए पारस्परिक विरोधी नीतियों में संलग्न रहते हैं। इस प्रक्रिया में यह स्वाभाविक है कि राज्य सन्तुलित शक्ति की खोज में रहे तथा किसी को भी प्रभुतासम्पन्न बनने से रोकने के लिए गुट तथा विरोधी गुट बनाए। परिवर्तन में रुचि रखने वाले राज्य सदैव ही उन राज्यों के विरुद्ध गुट बना लेते हैं जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सामान्य होती है कि यह एक ऐतिहासिक कानून का रूप धारण कर लेती है। यह कानून राज्यों के व्यवहार का विश्लेषण करता है। जब शक्ति-सन्तुलन शब्द का प्रयोग विश्लेषण के एक औजार के रूप में किया जाता है तो इसकी एक मुख्य विशेषता यह बन जाती है कि इसे सरकारों के लक्ष्यों से पृथक् कर दिया जाता है।

'शक्ति-सन्तुलन' शब्द का चौथा प्रयोग एक उपचार के रूप में (As Prescription) किया जा सकता है। विश्लेषण के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि सरकारें सजगता के साथ सन्तुलनकारी नियमों को अपनाती हैं। किन्तु ऐसे अनेक विचारक थे तथा हैं जो मानते हैं कि शक्ति-सन्तुलन सरकारों की निर्णायकारी प्रक्रिया का निर्देशक सिद्धान्त है अथवा होना चाहिए। ये विचारक हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने के बाद यह कहते हैं कि इस अवस्था ने ही शक्ति-सन्तुलन के समर्थक राज्यों को उन राज्यों के विरुद्ध सन्धिबद्ध होने के लिए मजबूर किया जो विश्व में अथवा किसी क्षेत्र में प्रभुत्व की स्थापना करना चाहते थे अथवा विश्वव्यापी राजतन्त्र का निर्माण करना चाहते थे। इनमें से कुछ का कहना है कि दुनिया के राज्य परस्पर-निर्भर होने के कारण आपस में बंधे हुए हैं। इसकी सामान्य सस्थाएँ हैं, सामान्य कानून की व्यवस्थाएँ हैं। इस

व्यवस्था में यदि कोई भी एक राज्य प्रभुत्वसम्पन्न बनना चाहेगा तो इसे सम्पूर्ण साव्यधी इकाई के विरुद्ध एक आक्रमण समझा जाएगा। यह राज्य-व्यवस्था स्वतन्त्र राज्यों से पूर्ण है तथा प्रभुत्व की इच्छा रखने वाले राज्य का विरोध प्रत्येक स्वेच्छा से ही करेगा। इस व्यवस्था में शक्ति-सन्तुलन का होना जरूरी था। इसने राज्यों की नीतियों का निर्देशन किया।

व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक रूप में शक्ति-सन्तुलन को विदेश-नीति की रचना के रूप में निर्देशक माना जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। मैटरनिक (Matternich) जैसे परम्परावादियों एवं उदारवादियों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के रूप में यह सिद्धान्त पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सम्पूर्ण संस्थागत यथास्थिति की रक्षा का प्रयास करता है। मैटरनिक के शब्दों में आधुनिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि एकता एवं शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्तों का प्रयोग हमारे सामने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करता है जिसमें कुछ राज्य मिलकर एक राज्य को प्रभुत्व प्राप्त करने से रोकते हैं तथा उसके प्रभाव को सीमित करते हैं।¹ इस प्रकार वे सामान्य कानून की ओर लौटाने के लिए बाध्य करते हैं।

शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त के आधार पर राज्य अपनी रक्षा का प्रयास करता है अथवा इसे राज्य-व्यवस्था की रक्षा के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आज समुक्त राष्ट्रसंघ शक्ति-सन्तुलन का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह संगठन आक्रमणकारी के इरादों को मोड़ने तथा उस पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास करता है।

इस प्रकार शक्ति-सन्तुलन शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है जो भिन्न होने के साथ-साथ कभी-कभी एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते हैं। यदि आप शक्ति-सन्तुलन की मान्यता को समझना या उसका मूल्यकित करना चाहे तो बड़ी परेशानी होगी क्योंकि अनेक लेखकों की यह प्रवृत्ति है कि इसके एक अर्थ का वर्णन करते-करते इसके दूसरे अर्थ का वर्णन करने लग जाते हैं और कुछ देर बाद पुनः उसी पूर्व अर्थ पर आ जाते हैं, किन्तु वही भी इस बात का उल्लेख तक नहीं करते कि उनके द्वारा शक्ति-सन्तुलन का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया गया है। डाइके के अनुसार, “हम सन्तुलन (Balance) शब्द का प्रयोग इस प्रकार करते रहे हैं कि मानो सभी इस बात को जानते हो कि इसका अर्थ क्या है, किन्तु वास्तविकता यह है कि कोई नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है।”²

शक्ति-सन्तुलन की स्थापना के तरीके

(Methods for Maintaining the Balance of Power)

राष्ट्र प्रायः शक्ति-सन्तुलन के सन्दर्भ में ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में आचरण और नीति निर्धारण करते हैं। अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार शक्ति-सन्तुलन कायम रखने के लिए राष्ट्रों द्वारा सामान्यतः अप्रोक्षित उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं—

1. **मुसाबजा या क्षतिपूर्ति (Compensation)**—एक देश द्वारा जब किसी प्रदेश पर अधिकार करके सन्तुलन को खतरा पहुँचाया जाता है तो उसे रोकने के लिए उस देश की भूमि पर अधिकार कर पुनः शक्ति-सन्तुलन की स्थापना कर दी जाती है। यह प्रथा अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में पर्याप्त लोकप्रिय थी। सन् 1713 की यूट्रेक्ट सन्धि द्वारा प्रथम बार स्पेन द्वारा अधिभूत भूमि को बाँट कर शक्ति-सन्तुलन स्थापित करने की कोशिश की गई थी। इतिहास में पोलैण्ड का तीन बार विभाजन किया गया और तीनों बार उसका बँटवारा इस प्रकार किया गया कि सन्तुलन कायम रहे। उस समय इस साधन की लोकप्रियता का कारण यह था कि भूमि के उपजाऊपन तथा लोगों की संख्या और गुण को राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। प्रदेशों के मुद्रावजों की व्यवस्था प्रायः युद्ध के बाद बड़ी और विजयी शक्तियों द्वारा पराजित व कमजोर देशों के विपरीत की जाती है। सन् 1870 से 1914 तक इस साधन का रूप केवल भूमि पर ही केन्द्रित नहीं रहा बल्कि प्रभाव क्षेत्रों (Spheres of Influences) को भी विभाजित किया जाने लगा। इस युग में कोई भी राज्य दूसरे राज्यों को राजनीतिक लाभ देने को तैयार नहीं होता था जब तक कि उसे यह ज्ञात न हो जाए कि बदले में उसे कितना लाभ मिल रहा है या मिल सकता है। मॉर्गेंथौ के शब्दों में राजनीतिक मामलों में इस प्रकार के कूटनीतिक समझौतों की सौदेबाजी सामान्य रूप में मुद्रावजों का ही सिद्धान्त है तथा यह मूल रूप से शक्ति-सन्तुलन से सम्बन्धित है।¹

2. **हस्तक्षेप एवं युद्ध (Intervention and War)**—शक्ति-सन्तुलन का दूसरा साधन हस्तक्षेप एवं युद्ध है। शक्ति-सम्बन्धों में परिवर्तन लाने के लिए कई बार युद्ध हुए हैं। हस्तक्षेप (Intervention) का अर्थ एक देश की विदेश-नीति के उन पहलुओं व कार्यों से लगाया जाता है जिन्हें दूसरा देश भी अपने कार्य मानता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रेटव्रिटेन ने यूनान व जोर्डन में हस्तक्षेप किया, अमेरिका ने क्यूबा, लेबनान व लाओस में तथा रूस ने उत्तरी कोरिया, हंगरी व पूर्वी यूरोप में यही किया। इन सभी हस्तक्षेपों का उद्देश्य शक्ति-सन्तुलन की स्थापना था या नहीं यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह उसका परिणाम अवश्य था। कुछ विचारक शक्ति-सन्तुलन की स्थापना के लिए हस्तक्षेप न करने की नीति को भी इतना ही महत्व प्रदान करते हैं। इस नीति का प्रयोग या तो उन कमजोर राष्ट्रों द्वारा किया जाता है जो लड़ाई में भाग लेने की शक्ति नहीं रखते या उन शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जो कि यथास्थिति राजनीतिक-व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं और शान्तिपूर्ण साधनों से ही शक्ति-सन्तुलन को बनाए रख सकते हैं। हस्तक्षेप की नीति का अन्तिम स्वर ही युद्ध है।

3. **सन्धियाँ (Alliances)**—यह साधन शक्ति-सन्तुलन की स्थापना के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाता है। जब एक राष्ट्र की बड़ी हुई शक्ति द्वारा

विश्व के शक्ति-सन्तुलन को चुनौती दी जाती है तो दूसरे राष्ट्र उसके विरुद्ध सन्धियाँ कर इस चुनौती का उत्तर देते हैं। सन्धियाँ दूसरे देशों पर आक्रमण करने की दृष्टि से भी की जा सकती हैं तथा आक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने के लिए भी। पहले प्रकार की सन्धियाँ आक्रमणात्मक (Offensive) हैं तथा दूसरे प्रकार की रक्षात्मक (Defensive)। वैसे दोनों का सम्बन्ध शक्ति-सन्तुलन से रहता है। आक्रमणात्मक सन्धियाँ शक्ति-सन्तुलन को अपने हित में बदलना चाहती हैं जबकि रक्षात्मक सन्धियाँ शक्ति-सन्तुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। पामर तथा पकिस के मतानुसार, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि राज्यों की प्रत्येक सन्धि का सम्बन्ध शक्ति-सन्तुलन से रहता है चाहे उसका विस्तार क्षेत्रीय हो, गोलार्द्धीय हो या विश्वव्यापी। समय की दृष्टि से कुछ सन्धियाँ अस्थायी एवं तात्कालिक आवश्यकता का परिणाम होती हैं जबकि दूसरी सन्धियाँ अधिक स्थायी एवं प्रभावपूर्ण होती हैं। किसी सन्धि को प्रभावपूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि सन्धि के लक्ष्यों को चाहे वे रक्षात्मक हो या आक्रमणात्मक, प्राप्त करने के लिए देशों के पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। दूसरे, सन्धि-कर्त्ता इकाइयों के हितों के बीच समानता होनी चाहिए। इसके अलावा युद्ध-कौशल, भूगोल, समान विचारधाराएँ, सांस्कृतिक समानताएँ और वर्तमान अर्थ-व्यवस्थाएँ आदि शर्तें एक सन्धि को अधिक स्थायी एवं टिकाऊ बनाने का काम करती हैं। अस्थायी एवं थोड़े समय के लिए आवश्यकता से प्रभावित होकर की गई सन्धियों के लिए ये सारी बातें आवश्यक नहीं होती। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सोवियत रूस व अमेरिका की सन्धि की गणना की जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों का विश्व-शान्ति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आक्रमणात्मक सन्धियों का उद्देश्य तो युद्ध होता ही है। यदि वे सफल हो जाएँ तो विश्व-शान्ति के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी सन्धियों को रोका जाना आवश्यक होते हुए भी कठिन है क्योंकि चाहे सन्धि स्पष्ट रूप से आक्रमणात्मक लक्ष्य से ही क्यों न की गई हो, इसकी इकाइयाँ विश्व को यही दिखाने का प्रयास करती हैं कि उनके गठबन्धन का लक्ष्य सुरक्षात्मक है। सच तो यह है कि प्रत्येक सन्धि उसकी इकाइयों के मतानुसार रक्षात्मक है, किन्तु उससे विरोधी उसको सदैव आक्रामक ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाया जा सकता। ये सभी प्रायः सन्देहशील प्रवृत्ति की होती हैं। आक्रमणात्मक सन्धियाँ होती हैं, इस कारण रक्षात्मक सन्धियों की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। सन्धियों की इकाइयाँ समय-समय पर बदलती रहती हैं। कभी-कभी एक राष्ट्र विश्व-साम्राज्य-निर्माण का स्वप्न देखता है तथा अपनी साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों को त्रियान्वित करने लगता है तो उससे प्रभावित या भयभीत राज्य परस्पर सन्धि-बद्ध होकर उसका विरोध करते हैं। दूसरी स्थिति में कुछ राष्ट्र दूसरे सन्धि-बद्ध राष्ट्रों के आक्रमणों का विरोध करने की दृष्टि से संगठित हो जाते हैं।

4 फूट डालो व शासन करो (Divide and Rule)—इसके अनुसार

एक देश नीति अपनाता है जिसने उसने उसके शत्रु आपस में न मिल सकें, इनमें फूट रहे और वे कमजोर बने रहें। फ्रांस ने जर्मनी के सम्बन्ध में और सोवियत युनियन ने शेष यूरोप के सम्बन्ध में इस नीति को अपनाने का प्रयास किया था। इसके द्वारा एक शक्तिशाली देश की शक्ति को घटा कर कम और सन्तुलन के निकट किया जाता है। बहुत समय से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में इस साधन का महत्त्व रहा है। ग्रेट-ब्रिटेन को इस नीति का सबसे बड़ा पण्डित माना जाता है। इसी नीति के आधार पर वह अपने बड़े साम्राज्य पर शासन करता रहा था। इसी कारण सोवियत युनियन द्वारा उन सभी योजनाओं और प्रस्तावों का विरोध किया जाता है जो पश्चिमी यूरोप में राजनीतिक व आर्थिक एकीकरण ला सकते हैं। इसका लक्ष्य मूलतः साम्यवादी व गैर-साम्यवादी गुट के बीच सन्तुलन कायम रखना है।

5. मध्यवर्ती राज्य (Buffer State)—विश्व जब दो गुटों में बँट गया तो उनके बीच सन्तुलन की स्थापना करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती राज्य के अस्तित्व का महत्त्व बढ़ गया जो राज्यों के बीच अवरोधक का काम करे। यदि विरोधी शक्तियाँ आमने-सामने हो जाएँ तथा उनके बीच कोई बाधक या मध्यवर्ती प्रदेश न हो तो सन्तुलन की स्थापना करना बड़ा कठिन हो जाएगा। मार्टिन वाइट के मतानुसार दुनिया का सबसे बड़ा अवरोधक क्षेत्र 'था' (Tha) है जो रूस को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करता था। यह क्षेत्र कमजोर व दूरस्थ राज्यों का था जिनके बीच भौगोलिक गढ़ बने हुए थे जिनमें राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। इस सदर्म में उन देशों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो असंलग्नता की विदेश-नीति अपना रहे हैं। भारत के नेतृत्व में ऐसे देशों का महत्त्व विश्व में शक्ति-सन्तुलन बनाए रखने की दृष्टि से बहुत बढ़ गया है।

6. शस्त्रीकरण तथा निःशस्त्रीकरण (Armament and Disarmament)—मॉर्गेनथो के मतानुसार शक्ति-सन्तुलन का एक तरीका यह है कि शक्तिशाली राष्ट्रों की शक्ति को कमजोर कर दिया जाए। उन्हीं के कथनानुसार शस्त्रों की दौड़ अथवा निःशस्त्रीकरण द्वारा ऐसा किया जा सकता है। शस्त्रों के नए-नए रूपों का आविष्कार कर आक्रामक राज्य के विरुद्ध सुरक्षा-व्यवस्थाओं को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। सैनिक तैयारी तथा आधुनिकतम शस्त्रों का प्रयोग कर विश्व में असन्तुलन को रोका जा सकता है। सिद्धान्त रूप में एक स्थायी सन्तुलन की स्थापना तभी की जा सकती है जब शस्त्रों की दौड़ की समाप्ति द्वारा विरोधी शक्तियों के शस्त्रों को सीमित कर दिया जाए। आज तक निःशस्त्रीकरण के अनेक प्रयास किए गए हैं, किन्तु उनका परिणाम अधिक सन्तोषजनक नहीं रहा। स्पेन के एक विद्वान् सेल्वाडोर मादरियागा (Salvador Madariaga) के मतानुसार, "निःशस्त्रीकरण की समस्या, निःशस्त्रीकरण की समस्या नहीं है, यह वास्तव में विश्व-समुदाय के संगठन की समस्या है।"¹ पामर तथा पकिंस के मतानुसार मूल रूप में यह शक्ति-सन्तुलन की स्थापना की समस्या है।

शक्ति-सन्तुलन तथा राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले अन्य तत्त्व
(Balance of Power and other Limiting Factors)

कई कारणों से जब राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले तत्त्व के रूप में शक्ति-सन्तुलन का महत्त्व कम हो गया तो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति-सन्तुलन के व्यावहारिक विक्तियों की खोज की जाने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने शक्ति-सन्तुलन की आलोचना करके विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) पर जोर दिया। सामूहिक सुरक्षा के अधीन सभी देश परस्पर सम्बद्ध रहेंगे अतः यह कहा जाता है कि किसी प्रकार की सन्धियों की, अस्त्र-शस्त्रों की दौड़ की, राजनीतिक मतभेदों की तथा परस्पर सघर्ष की कोई आवश्यकता न रहेगी। ये सभी बातें शक्ति-सन्तुलन में पाई जाती हैं। क्विंसी राइट (Quincy Wright) का मत है कि सामूहिक सुरक्षा से शक्ति-सन्तुलन का सम्बन्ध एक ही साथ पूरक (Complementary) तथा विरोधी (Antagonistic) दोनों रूपों में है। सामूहिक सुरक्षा का आधार शक्ति-सन्तुलन है जो ऐसे स्थायित्व का निर्माण करता है जिसमें नीति की क्रियाओं को स्थायित्व देना सम्भव होना है। सामूहिक सुरक्षा के उदाहरण हैं—यूरोप का मेल (Concert of Europe), राष्ट्रसंघ (League of Nations) और संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations)—ये तीनों ही शक्ति-सन्तुलन से सम्बन्धित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के साथ भी शक्ति-सन्तुलन का वही सम्बन्ध है जो क्विंसी राइट द्वारा शक्ति-सन्तुलन और सामूहिक सुरक्षा के बीच बताया गया है। ओपेनहेम (L. F. Oppenheim) के मतानुसार शक्ति-सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्रों का कानून (A Law of Nations) बना तभी रह सकता है जबकि विश्व में शक्ति का सन्तुलन या तुल्यभाविता रहे। राष्ट्रों के कोई सम्प्रभु व शक्तिशाली व्यवस्था न होने के कारण केवल शक्ति-सन्तुलन द्वारा ही ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है कि एक राष्ट्र दूसरे पर बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग न कर सके। कुछ विचारकों के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून शक्ति-सन्तुलन को धीरे-धीरे सामूहिक सुरक्षा में परिणत कर देगा। क्विंसी राइट का मत है कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में शान्तिपूर्ण साधनों से कानून द्वारा प्रशामित विश्व का निर्माण करना हो तो राजनीतिज्ञों को अधिक सश्लिष्ट सन्तुलन (Complicated Balance) का प्रयत्न करना होगा।

शक्ति-सन्तुलन पर मॉर्गेंथौ के विचार

(The Concept of Morgenthau on Balance of Power)

शक्ति-सन्तुलन से सम्बन्धित कोई भी अध्ययन तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक इस विषय के प्रमुख विचारक मॉर्गेंथौ के विचारों का वर्णन न किया जाए।

1. मॉर्गेंथौ के मतानुसार शब्द 'शक्ति-सन्तुलन' का प्रयोग तीन भिन्न अर्थों में किया जा सकता है—(i) नीति के रूप में जो कुछ निश्चिन कार्य करना चाहनी है, (ii) वास्तविक कार्यों के रूप में एवं (iii) शक्ति के समान विन्यास के रूप

में। उनका कहना है कि जब 'शक्ति-सन्तुलन' शब्द का प्रयोग बिना किसी विवेचन (Qualification) के किया जाता है तो यह कार्य के वास्तविक स्तर का बोध कराता है जिसमें कुछ राष्ट्रों के बीच शक्ति का लगभग समान वितरण कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में मॉर्गन्थो के अनुसार शक्ति-सन्तुलन का अर्थ तुल्यभारिता है। किन्तु जैसा कि क्लॉड (I. L. Claude) का मत है, मॉर्गन्थो द्वारा शक्ति-सन्तुलन शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है तथा इसकी सूचना भी पाठक को नहीं दी गई है।¹ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग शक्ति के वितरण के रूप में भी किया है। मॉर्गन्थो की पुस्तक का अध्ययन करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस शब्द का प्रयोग कब किस अर्थ में किया गया है। सच तो यह है कि उन्होंने इन शब्द का प्रयोग पाँच अर्थों में किया है।

2. मॉर्गन्थो ने शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त को अपरिहार्य (Inevitable) बनाया है। उनका मत है कि शक्ति-सन्तुलन तथा इसे बनाए रखने वाली नीतियाँ न केवल अपरिहार्य हैं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्रों के समाज में स्थायित्व लाने वाले मूल तत्त्व हैं।

3. मॉर्गन्थो के अनुसार शक्ति-सन्तुलन विदेश-नीति का एक सामान्य साधन (Universal Instrument) है। इसका प्रयोग अपनी स्वतन्त्रता चाहने वाले प्रत्येक राष्ट्र द्वारा प्रत्येक समय में किया गया है। यह शक्ति के संघर्ष का स्वाभाविक एवं अपरिहार्य परिणाम है।

4. मॉर्गन्थो के शक्ति-सन्तुलन सम्बन्धी विचारों में कुछ असंगतियाँ हैं। जब वे शक्ति-सन्तुलन को अपरिहार्य तथा स्वाभाविक बताते हैं तो वे यह स्पष्ट नहीं करते कि यह शक्ति-सन्तुलन के कौन से रूप पर लागू होता है। एक ओर वे इसे मनुष्यकृत मानते हैं। इसी प्रकार शक्ति-सन्तुलन का सामान्य रूप भी आजकल ज्ञान नहीं होता।

5. तुल्यभारिता को अपरिहार्य मान कर अमेरिकी विदेश-नीति के गुण को गुंथारने के लिए मॉर्गन्थो ने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। शक्ति-सन्तुलन को अपरिहार्य मानने का उनका अर्थ क्या हो सकता है यह जानना बड़ा कठिन है। उनके विचारों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति-सन्तुलन की अपरिहार्यता से उनका अर्थ न तो यह है कि तुल्यभारिता (Equilibrium) की स्थिति सदैव कायम रहती है और न यह कि राज्यों की नीतियों का लक्ष्य सदैव ऐसी स्थिति कायम करने का होता है या उसकी रक्षा करने का मॉर्गन्थो का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में शान्ति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति-सन्तुलन के अतिरिक्त इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय कानून, सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आदि साधनों का भी विकास किया गया है। इस मान्यता का स्पष्ट अर्थ यह है कि शक्ति-सन्तुलन को अपरिहार्य नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका कार्य सम्भालने के लिए दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं। मॉर्गन्थो का कथन है कि राष्ट्रों के सामने

दूसरा रास्ता ही नहीं होता। एक विवेकपूर्ण विदेश-नीति सदैव शक्ति के सन्तुलन का सिद्धान्त अपनाती है, किन्तु जो देश इसका बहिष्कार करता है, या तो उसे विश्व को विजय करना पड़ेगा अथवा वह नष्ट हो जाएगा।

शक्ति-सन्तुलन सिद्धान्त का मूल्यांकन

(An Evaluation of Balance of Power System)

शक्ति-सन्तुलन का सिद्धान्त अतिशय प्रशंसा और गम्भीर आलोचना दोनों ही का पात्र रहा है। विद्वानों ने विगत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास की विवेचना शक्ति-सन्तुलन के आधार पर की है और उदाहरण देते हुए इसे भला-बुरा कहा है।

शक्ति-सन्तुलन के समर्थकों ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालक माना है। यथार्थवादी विचारकों ने इसका समर्थन दण्ड-नीति के आधार पर किया है। मॉर्गन्थो के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माता के रूप में शक्ति-सन्तुलन इतिहास के विभिन्न स्तरों पर सफल रहा है। इसने कभी भी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया है जो दूसरों की स्वतन्त्रता को समाप्त कर सके।”¹ डनिस क्लाड ने स्वीकार किया है कि “शक्ति-सन्तुलन-व्यवस्था इस रूप में कार्य कर सकती है कि तुल्यभारिता (Equilibrium) की रचना और सम्भाल कर सके, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसा करे और वह परिणामों को उत्पन्न करने वाली उपयुक्त व्यवस्था भी नहीं है।”²

बहुत से विचारकों का मत है कि शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था ने कई बार युद्धों को रोका है। फ्रेडरिक गेंज (Friedric Geniz) का कहना है कि “युद्ध प्रायः तभी उत्पन्न होता है जब एक देश अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है।” क्लेमेंसो (Clemenceau) का मत था कि प्रथम विश्व-युद्ध सन्तुलन के टूटने का परिणाम था। यदि शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था कायम रहनी तो निश्चय ही विश्व-युद्ध न छिड़ता। विवसी राइट के शब्दों में, “शक्ति-सन्तुलन एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक राज्य में निरन्तर यह विश्वास पैदा करती है कि यदि उसने आक्रमण करने का प्रयत्न किया तो दूसरे राज्यों के संगठित प्रयास द्वारा उसका विरोध किया जाएगा।”³

जो आलोचक शक्ति-सन्तुलन को युद्ध का कारण मानते हैं वे मूल जाते हैं कि यह व्यवस्था किसी शान्तिवादी दर्शन से सम्बन्धित नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि राज्यों को अकेले ही या संगठित रूप से शक्ति का प्रयोग करने को तत्पर रहना चाहिए, यहाँ तक कि ऐसी शक्ति को कुचन देना चाहिए जो भविष्य में उनकी स्वयं की रक्षा को चुनौती दे सकती है। इस प्रकार ‘युद्ध’ तुल्यभारिता की स्थापना के लिए आवश्यक हो सकता है अथवा तुल्यभारिता के द्वारा युद्ध रोका जा सकता है, दोनों ही बातें बहुत कुछ अंशों में सत्य हैं।

- 1 *Morgenthau and Thompson : Principles and Problems of International Politics*, p. 103.
- 2 *I. L. Claude : Power and International Relations*, p. 66.
- 3 *Quincy Wright : A Study of War I*, p. 254.

इसके समर्थकों ने शक्ति-सन्तुलन की मान्यता के अनेक लाभ बताए हैं जैसे, यह आक्रमणों को हतोत्साहित कर राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा करता है, यह विनय-योजनाओं को हतोत्साहित कर विश्व-साम्राज्य के निर्माण को रोकता है, यह अव्यवस्था और गड़बड़ी को रोक कर यथास्थिति (Status-quo) स्थिर रखने में सहायक होता है। हो सकता है कि प्रतिरोध का यह साधन असफल हो जाए और युद्ध न रुक सके किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि शान्ति-स्थापना शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त की भारी देन है।

आलोचना के पक्ष में कहा जाता है कि शक्ति-सन्तुलन ने चाहे यूरोपीय राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा में कुछ प्रयत्नों पर सहयोग दिया हो, लेकिन युद्ध और आक्रमण को रोकने में यह एक प्रभावशाली व्यवस्था सिद्ध नहीं हुई है। 20वीं शताब्दी में इसके द्वारा इटली को इथियोपिया पर आक्रमण करने से नहीं रोका जा सका और जापान को चीन का एक बहुत बड़ा भाग हस्तगत करने से भी नहीं रोका जा सका। यूरोप में सन् 1930 में महा-शक्तियों के बीच जो सन्धि-समझौते किए गए वे अनेक राज्यों के मूल्य पर सम्पन्न हुए। हिटलर की माँग पर चैकोस्लोवाकिया को समायन कर दिया गया और पोलैण्ड को रूस तथा जर्मनी के बीच विभक्त कर दिया गया। चैम्बरलेन तथा दत्तादियर ने सोचा था कि हिटलर के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाकर युद्ध को रोका जा सकता है, किन्तु इतिहास साक्षी है कि जब स्थित सन्तुलन को बिगाड़ने वाले राज्य की माँगों को स्वीकार किया जाता है तो वह और अधिक प्रोत्साहित होता है।

ब्रिक्सन, हल, हजबेल्ड आदि ने शक्ति-सन्तुलन को संघर्षों और युद्धों का कारण मानते हुए इसके स्थान पर सामूहिक-सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया है। ब्रिक्सन ने सन् 1971 में घोषित किया था कि अब मानव-जाति जीवन की स्वतन्त्रता की खोज में है न कि शक्ति-सन्तुलन की खोज में। मॉर्गेन्थो ने स्वीकार किया है कि शक्ति-सन्तुलन न केवल पोलैण्ड की रक्षा करने में ही असफल रहा, अपितु मुदावजे के रूप में भूमि वितरण के नाम पर पोलैण्ड को ही विखण्डित कर दिया गया। शक्ति-सन्तुलन ने किसी राज्य-विशेष या पूरी राज्य-व्यवस्था के किसी भी कार्य को युद्ध के साधन के अलावा अन्य किसी साधन से पूरा नहीं किया। मॉर्गेन्थो के मतानुसार इसका कारण शक्ति-सन्तुलन की तीन कमजोरियाँ हैं—(i) यह अनिश्चित है, (ii) यह अवास्तविक है, (iii) यह अपर्याप्त है।¹

शक्ति-सन्तुलन सिद्धान्त की मान्यता का मूल्यांकन करते हुए पैडलफोर्ड एव लिंकन ने लिखा है कि इस सिद्धान्त द्वारा यह दावा किया जाता है कि इसने युद्धों का विरोध और हतोत्साहित किया है, राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा की है और एक राज्य अवस्था राज्य-समूह द्वारा अनुचित प्रभुत्व स्थापित करने पर रोक लगाई है, इस प्रकार इसने बहुराज्य-व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता की है। इतिहास साक्षी

है कि शक्ति-सन्तुलन की राजनीति ने कुछ युद्धों को रोका, कुछ को विलम्बित और कुछ को हतोत्साहित किया, लेकिन युद्ध की दृष्टि में हम इसे एक अच्छा औपधि नहीं मान सकते, क्योंकि यह अतीत काल में अनेक युद्धों को रोकने में असफल रहा है और भविष्य में भी युद्ध का एक सफल अवरोधक नहीं है। शक्ति-सन्तुलन की नीति को व्यावहारिकता के आधार पर समर्थन दिया जाता है। यह कहा जाता है कि आक्रमक शक्ति को मर्यादित करने का यह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय-सुरक्षा कायम रखता है। शक्ति-सन्तुलन का नैतिक रूप में विश्लेषण करना उपयुक्त है क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति का अस्तित्व एक तथ्य है और भविष्य में भी यह एक तथ्य बना रहेगा। चाहे सन्तुलन को नैतिक माना जाए या अनैतिक, इसका अस्तित्व हर युग में रहेगा। शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था में आने वाले सम्प्रभु राज्यों के निर्णयों को उनके सहयोगियों द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक नेताओं पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। वे अपने राष्ट्रीय राजनीतिक तन्त्रों और दबाव-समूहों द्वारा प्रभावित होते हैं। शक्ति-सन्तुलन में सहयोग करते हुए भी व्यक्तिगत राज्य द्वारा एक विषय की किस तरह व्याख्या की जाएगी यह किसी समस्या-विशेष की प्रकृति पर निर्भर करती है।

इससे इन्कार करना कठिन है कि शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् की एक वास्तविकता बन चुकी है तथापि इसमें अनेक सैद्धान्तिक और मध्य स्थायी तथा सम-स्तरीय सम्बन्धों पर विचार होता है, लेकिन औद्योगीकरण तकनीकी विकास, राजनीतिक परिवर्तन आदि अनेक ऐसे तत्त्व हैं जो शक्ति-वितरण में निरन्तर परिवर्तन लाते रहते हैं। इनका मूल्यांकन करना मुगम नहीं है। पुनश्च-शक्ति-सन्तुलन में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पक्षों का बदलना सम्भव नहीं है। वर्तमान में राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों से राजनीतिक, आर्थिक मनोवैज्ञानिक आदि स्तरों पर बंधे हुए हैं और गुटबन्धियों से निकलना दुष्कर है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान ढाँचे में शक्ति-सन्तुलन-सिद्धान्त की सार्थकता विवादास्पद है। अधिकांश मत यही है कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था शिथिल पड़ गई है। पामर एव पकिंस के अनुसार, "वर्तमान विश्व की परिस्थितियाँ शक्ति-सन्तुलन-व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं हैं, तथापि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक प्रभावकारी रूप है और अभी तक इसका कोई प्रभावकारी विवरण नहीं बन पाया है।" रोजर्स जी मास्टर्स जैसे विचारक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बहुगुदीय प्रनिरूप (Multi Block Model) के समर्थक हैं और वर्तमान बहुपक्षीय व्यवस्था को शक्ति-सन्तुलन के अधिक समुचित मानते हैं।¹

सामूहिक सुरक्षा (Collective Security)

अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने का एक-दूसरा साधन सामूहिक सुरक्षा

1 Rogers G Masters : "A Multi-Block Model of the International System" in American Political Science Review, Dec., 1961, pp. 789-98.

है जिसमें विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से संबन्धित होकर सम्भावित आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था में जो सन्धियों की जाती हैं उनका लक्ष्य एक देश या कुछ देशों के गुट का विरोध करना, उन पर आक्रमण करना या उनके आक्रमण से अपनी रक्षा करना होता है, किन्तु सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में विरोधी अस्पष्ट एवं सम्भावित होता है। इस प्रकार की सन्धि के अनुसार किसी भी एक इकाई पर आने वाला सफ़ट या आक्रमण सन्धिबद्ध सभी इकाइयों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाता है और सामूहिक रूप से ही उसका विरोध किया जाता है। इस व्यवस्था को शान्तिपूर्ण एवं शान्तिवर्धक माना जाता है। क्लाउड (Claude) के मतानुसार, केन्द्रीकरण की दृष्टि से सामूहिक सुरक्षा बीच की व्यवस्था है। इनमें शक्ति-सन्तुलन से अधिक केन्द्रीकृत प्रवर्ध होना है, किन्तु विश्व-सरकार की मान्यता से यह कम रहता है।¹

सामूहिक सुरक्षा का अर्थ

(The Meaning of Collective Security)

सामूहिक सुरक्षा जैसा कि शब्दों से ही प्रकट होता है, देश द्वारा सुरक्षा के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्नों से सम्बन्धित होती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने सुरक्षा प्रयत्नों में सचेत रहता है, किन्तु यदि उन पर सफ़ट आता है अथवा आक्रमण किया जाता है तो सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में सम्मिलित सभी राष्ट्र उसी सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से सगठित हो जाते हैं।

सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को जॉन स्वज़न बर्गर (John Schwazen Berger) ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथवा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यन्त्र कहा है। साम्राज्यवादी तथा युद्ध-प्रिय देश विश्व-शान्ति को चुनौती देते रहते हैं। सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था का लक्ष्य है कि इस प्रकार की चुनौतियों का सक्षम मुकाबला सामूहिक रूप से किया जाए। मॉर्गेन्थौ के अनुसार सामूहिक सुरक्षा की कार्यकारी व्यवस्था में सुरक्षा की समस्या किसी अकेले राष्ट्र की समस्या नहीं होती बल्कि उन सभी राष्ट्रों की समस्या होती है जो इस व्यवस्था के अन्तर्गत आपस में प्रतिबद्ध होते हैं। 'एक सबके लिए और सब एक के लिए' (One for all and all for one) यह सामूहिक सुरक्षा का नारा है।² कुछ देशों में यह व्यवस्था शक्ति-सन्तुलन का विस्तृत रूप कही जा सकती है, लेकिन दोनों में निश्चिन्त रूप से आधारभूत अन्तर है।

युद्ध को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की अगिवृद्धि करने के प्रभावी साधन के रूप में सामूहिक सुरक्षा का विचार कुछ आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है—

प्रथम, सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था इस रूप में पर्याप्त शक्ति-सम्पन्न हो ताकि वह आक्रमणकारी राज्य का मुकाबला कर सके। यह व्यवस्था प्रत्येक अवसर पर

1 I. L. Claude: Power and International Relations, p. 94.

2 Morgenthau: op. cit., pp. 412-413

शक्ति-संचय करने की इतनी जबरदस्त स्थिति में न हो कि आक्रामक राष्ट्र आक्रमण करने का दुस्साहस न करे।

द्वितीय, सामूहिक रूप से आक्रमण का मुकाबला करने की सहमत राष्ट्रों की सुरक्षा सम्बन्धी मान्यताओं और नीतियों में यथासम्भव समानता हो।

तृतीय, ऐसे सभी राष्ट्र अपने परस्पर-विरोधी राजनीतिक हितों (Conflicting Political Interests) को सामूहिक सुरक्षात्मक कार्यवाही के हितार्थ बलिदान करने को तत्पर रहे।

चतुर्थ, सभी सम्बन्धित राष्ट्र यथास्थिति स्थापित रखना अपने राष्ट्रीय हित में समझे।

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि शक्तियुक्त एकता का विरोध करने से पूर्व आक्रमणकारी राज्य भली प्रकार सोच-विचार कर लेगे। इस व्यवस्था में प्रत्येक देश को अपनी सम्प्रभुता को कुछ मर्यादित करना पड़ता है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय सकल्प (National Will) का समर्पण सामूहिक निर्णय के लिए कर दिया जाता है। सफल सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में सैन्य एवं शस्त्र-बल पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है। इस व्यवस्था का लक्ष्य केवल सामान्य शत्रु अथवा आक्रमण की चुनौती का सामना करना ही नहीं होता, बल्कि यह इसाइयो के विकास को प्रतिरोधक के रूप में भी प्रभावित करती है। सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में सभी अथवा अधिक से अधिक सस्या में बड़ी शक्तियों को सम्मिलित करना होना है क्योंकि किसी भी विकट संकट का सामना करने की शक्ति उनमें ही होती है। सामूहिक सुरक्षा-सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में ये पूर्व-धारणाएँ विद्यमान रहती हैं कि युद्ध की सम्भावनाएँ सदा विद्यमान रहने वाली हैं तथा आक्रामक शक्तियों को युद्ध करने से तभी रोका जा सकता है जब उनके लिए जबरदस्त शक्ति और विरोध का आतंक पैदा कर दिया जाए। इस प्रकार 'युद्ध' और निवारण के रूप में 'शक्ति'—ये दोनों तत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता के रूप में स्वीकार किए गए हैं।

सामूहिक सुरक्षा के विचार का विकास

(Development of the Collective Security Idea)

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को दिया जाता है तथापि इस विचार का आरम्भ 17वीं शताब्दी की ओस्नेब्रूक (Osnabruck) की सन्धि से माना जाता है। इस सन्धि की 17वीं धारा में किसी भी सम्भावित शत्रु के विरुद्ध सामूहिक बंदम की बात कही गई थी। 19वीं शताब्दी में विलियम पेन तथा विलियम पिट ने यूरोप में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए सामूहिक सुरक्षा जैसी व्यवस्था का विचार प्रचारित किया। विलियम पिट ने यूरोपीय महाशक्तियों को सुभाषित दिया कि वे भविष्य में शान्ति एवं व्यवस्था को समाप्त करने वाले किसी भी आक्रमण का सामूहिक रूप से विरोध करने की एक प्रभावी योजना बना लें।

सामूहिक सुरक्षा पद्धति का वास्तविक रूप 20वीं शताब्दी में प्रवृत्त हुआ। सन् 1910 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल्यम विल्सन ने कहा कि "शान्ति-प्रिय महाशक्तियाँ एक शान्ति-संघ (League of Peace) का निर्माण करें ताकि न केवल उनके बीच शान्ति स्थापित रहे बल्कि किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा भी यदि शान्ति भंग की कार्यवाही हो तो समुचित शक्ति द्वारा उसे रोका जा सके।" सन् 1910 में ही एक अन्य विचारक वॉन वुल्लेनहोवन (Von Wollenhoven) ने भी इसी प्रकार की एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सुझाव दिया जिसका अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समर्थन दिया गया।

सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था के अभियान को विशेष लोकप्रिय बनाने में प्रथम महायुद्ध काल में राष्ट्रपति विल्सन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। विल्सन ने शान्ति-स्थापना के लिए 'सामूहिक-व्यवस्था' की जबरदस्त वकालत की और विशेषतः उन्हीं के प्रयत्नों से पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप में राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ सामूहिक सुरक्षा की व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया।

दुर्भाग्यवश राष्ट्रसंघ की सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था विभिन्न कारणोंवश असफल सिद्ध हुई, तथापि सामूहिक सुरक्षा का विचार द्वितीय महायुद्ध काल में ही और भी सजीव हो गया तथा नवीन विश्व-संस्था अर्थात् राष्ट्र-संघ में राजनीतियों और विश्व-नेताओं ने और भी मजबूती के साथ सामूहिक सुरक्षा को प्रस्थापित किया। चार्टर के अध्याय 7 तथा महासभा के 'शान्ति के लिए एकता' प्रस्ताव द्वारा सामूहिक सुरक्षा-पद्धति का विकास किया गया। वर्तमान विश्व-संस्था के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा-पद्धति निश्चित रूप से राष्ट्रसंघ की तुलना में श्रेष्ठतर व्यवस्था है।

सामूहिक सुरक्षा और शक्ति-सन्तुलन

(Collective Security and Balance of Power)

सामूहिक सुरक्षा को प्रायः शक्ति-सन्तुलन का विकला माना जाता है। सामूहिक सुरक्षा के व्यावहारिक रूप के जनक विल्सन ने अपने विचारों का प्रतिपादन शक्ति-सन्तुलन के विरोध में किया था। वे मानते थे कि शक्ति-सन्तुलन में राष्ट्र-प्रतियोगितापूर्ण सन्धि में बढ हो जाता है तथा बाध्यकारी शक्ति (Coercion) का प्रयोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तथा स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जबकि सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में देशों के सहयोग का अर्थ होता है सभी की न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना जिसमें बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग सामान्य शान्ति की स्थापना के लिए किया जाता है। क्लाउड (I. L. Claude) ने लिखा है कि "विल्सन से लेकर आज तक सामूहिक सुरक्षा के सभी समर्थक इसे शक्ति-सन्तुलन से भिन्न रूप में परिभाषित करते रहे हैं।"¹

विभिन्नताएँ (The Differences)—शक्ति-सन्तुलन एवं सामूहिक सुरक्षा की मान्यताओं के बीच कुछ अन्तर हैं जो मुख्यतः अप्रतिष्ठित हैं—

1. सामूहिक सुरक्षा एक सार्वभौम सन्धि (Universal Alliance) है जो प्रतियोगी सन्धियों (Competitive Alliances) से भिन्न है जिनको 'शक्ति-सन्तुलन' की विशेषता माना जाता है। कॉर्डेल हल (Cordell Hull) ने संयुक्तराष्ट्रसंघ के बारे में लिखा है कि यह कुछ संगठित राष्ट्रों के विरुद्ध सन्धि नहीं है वरन् प्रत्येक आक्रमणकारी के विरुद्ध है। यह सन्धि युद्ध के लिए नहीं वरन् शक्ति के लिए है।¹ यह कथन दोनों मान्यताओं के मूल अन्तर को स्पष्ट करता है।

2 शक्ति-सन्तुलन की मान्यता दो या दो से अधिक विरोधी गुटों की कल्पना पर आधारित है जो परस्पर संघर्षशील प्रकृति के हैं, किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता 'एक विश्व' (One World) है जो सहयोग के आधार पर व्यवस्था का निर्माण करने के लिए संगठित होती है।

3. यद्यपि दोनों मान्यताएँ संघर्ष व सहयोग को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के मूलनस्त्व मानती हैं तथा संघर्ष का मुकाबला करने के लिए सहयोग की सिफारिश करती हैं, किन्तु शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था के निर्माण के लिए संघर्षपूर्ण सहयोग चाहता है जबकि सामूहिक सुरक्षा संघर्ष को प्रतिबन्धित रखने के लिए सामान्य सहयोग पर बल देती है।

4 शक्ति-सन्तुलन सीमित गुटबन्दी द्वारा ही आक्रमणकारी का विरोध करता है तथा यह मानता है कि संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सर्वकालीन विशेषता है, किन्तु सामूहिक सुरक्षा सामान्य सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का मुकाबला करने को तैयार रहती है तथा यह मानती है कि आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर केवल अपवाद है, नियम नहीं।

5. सामूहिक सुरक्षा यह मान कर चलती है कि किसी भी राष्ट्र द्वारा किसी भी राष्ट्र पर कभी भी किया गया आक्रमण विश्व-शान्ति के लिए खतरा है और इसका विरोध करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को बटिवद्ध रहना चाहिए, किन्तु शक्ति-सन्तुलन की मान्यता इससे भिन्न है। इसमें एक राष्ट्र पर आक्रमण होने के समय दूसरी सहयोगी इकाइयाँ उसका मुकाबला करने में तभी साथ देंगी जब वह उनके हितों से भेन रखता हो। यदि एक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उस आक्रमण से प्रभावित नहीं होता तो वह युद्ध में भाग लेने से विमुख हो सकता है।

6 इस प्रकार सन्तुलन व्यवस्था व्यवहारवादी (Pragmatic) है तथा एक राष्ट्र को आक्रमण का विरोध करने की केवल तभी सलाह देती है जब आक्रमण उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए घातक हो। किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता में कुछ अधिक प्रभावशाली संझान्तिब पुट है क्योंकि यह राज्य की सर्वत्र आक्रमण का विरोध करने को प्रेरित करता है क्योंकि उसका हित आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

7. शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था बहुत अस्त-व्यस्त होती है। यह अनेक स्वायत्त एवं स्वनिर्देशित राज्यों से मिलकर बनती है जिनमें बड़े राज्य छोड़े ही होते हैं, किन्तु

सामूहिक सुरक्षा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को संगठनात्मक रूप देने की कोशिश की जाती है।

क्विंसी राइट के मतानुसार सामूहिक सुरक्षा व शक्ति-सन्तुलन के बीच यही अन्तर है जो कि कला (Art) और प्रकृति (Nature) के बीच होता है।

समानताएँ (The Similarities)—शक्ति-सन्तुलन व सामूहिक सुरक्षा के बीच उक्त अन्तरों के अतिरिक्त निम्न समानताएँ भी हैं—

1. कहा जाता है कि शक्ति-सन्तुलन की योजना का आधार दूसरे पक्ष की आक्रमणकारी सामर्थ्य (Aggressive Capacity) है जबकि सामूहिक सुरक्षा आक्रामक नीति पर अधिक ध्यान देती है। यह आंशिक सत्य है क्योंकि शक्ति-सन्तुलन में दूसरे पक्ष की केवल आक्रमणकारी सामर्थ्य पर ही ध्यान नहीं दिया जाना बल्कि आक्रामक नीति को भी देखा जाता है।

2. दोनों मान्यताएँ प्रतिरोध (Deterrence) के सिद्धान्त की भूमि पर आधारित हैं। शक्ति-सन्तुलन में स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाया जाता है कि विरोधी मुँह न उठा सकें, सामूहिक सुरक्षा में भी शक्ति का एकीकरण कर आक्रमणकारी की महत्वाकांक्षाओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

3. शक्ति-सन्तुलन का आधार तुल्यभारिता तथा सामूहिक सुरक्षा का आधार प्रबलता (Preponderance) माना जाता है, किन्तु असल में तुल्यभारिता का रूप भी निश्चित नहीं है। शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था में कोई पक्ष किसी देश से यह नहीं कहता कि दूसरा पक्ष कमजोर है, अतः सन्तुलन के स्थापनार्थ वह उस पक्ष के साथ मिल जाए। इस प्रकार दोनों मान्यताओं के बीच वास्तविक अन्तर बहुत कम है।

4. दोनों ही व्यवस्थाएँ 'शान्ति के लिए युद्ध' (War for Peace) में विश्वास रखती हैं तथा कहती हैं कि शान्ति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि लड़ने की इच्छा पैदा करने की सामर्थ्य का विकास किया जाए।

5. दोनों ही राज्यों के सामूहिक सहयोग में विश्वास करते हैं यद्यपि आक्रमणकारी अर्थात् शान्ति को चुनौती देने वाला स्पष्ट नहीं होता।

6. दोनों ही अवधारणाओं की समानता उन आधारभूत परिस्थितियों के आधार पर भी बतायी जा सकती हैं जो दोनों ही व्यवस्थाओं के सफल व्यवहार के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए, दोनों में शक्ति का फैलाव (Diffusion) इतना किया जाता है कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र या पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को खतरा न पहुँचा सके। दुनिया का दो गुटों में बँट जाना (Bipolarity) दोनों ही मान्यताओं के सफल संचालन के लिए घातक माना जाता है। दोनों में लचीली नीति (Flexible Policy) अपनाई जाती है ताकि आवश्यकतानुसार पुराने शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बनाने का मार्ग अवलम्बित हो जाए। प्रजातन्त्र के इस गुण में दोनों ही धारणाएँ लोकमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। दोनों की स्थापना प्रायः एक-ही दुनिया में की

जाती है। विश्व के जिन परिवर्तनों ने शक्तिशाली सन्तुलन के मार्ग में बाधा डाली है वे सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था के सफल संचालन में भी बाधक हैं। एडवर्ड वी. गुलिक (Edward V. Gulick) के मतानुसार शक्ति-सन्तुलन का विकास हुआ है। सन्धि (Alliance), सम्मिलन (Coalition) तथा सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) इसके विकास-क्रम के सोपान हैं। क्लाउड (I. L. Claude) का कहना है कि, “निष्कर्ष रूप में अनेक विचारकों ने यह स्वीकार किया है कि सामूहिक सुरक्षा को शक्ति-सन्तुलन का एक परिवर्द्धित संस्करण मानना चाहिए न कि पूरी तरह से भिन्न और शक्ति-सन्तुलन का विकल्प।”¹ शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त की मान्यताएँ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को पूरक हैं।

सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रसंघ

(Collective Security and the League of Nations)

सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा ने राष्ट्रसंघ के रूप में प्रथम बार संगठनात्मक रूप धारण किया। सविदा के अनुच्छेद 10 में व्यवस्था थी कि “संघ के सदस्य उसके सभी सदस्यों को प्रादेशिक एकता और राजनीतिक स्वतन्त्रता का सम्मान करने तथा उन्हें बाह्य आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित रखने का वचन देते हैं। इसी प्रकार के किसी आक्रमण के होने अथवा इस प्रकार के आक्रमण की घमकी अथवा भय उत्पन्न होने की अवस्था में परिपक्व उन साधनों के बारे में परामर्श देगी जिनसे इस उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सके।” इस अनुच्छेद में प्रस्थापित राष्ट्रसंघ का यही प्रसिद्ध ‘सामूहिक सुरक्षा’ का सिद्धान्त था। अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत सदस्य-राष्ट्र आ शयकता पड़ने पर सामूहिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने को वचनबद्ध थे। यह अलग बात है कि यथार्थ में इस अनुच्छेद की कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। पामर एवं पकिस के अनुसार संघ के सदस्यों द्वारा इसके अर्थों की एकपक्षीय व्यवस्थाएँ की गईं तथा बातों के सिवाय और कुछ नहीं किया गया।

अपने जन्म के प्रारम्भिक वर्षों में संघ द्वारा कुछ समस्याओं को सुलझाया गया। किन्तु बड़ी व महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करते समय बड़े राष्ट्रों द्वारा इसके नियमों का उल्लंघन किया गया। सन् 1931-33 में मंचूरिया ने संकट से लेकर हिटलर के आक्रमणों की शृंखला तक अर्थात् द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ तक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा के अभाव में एक के बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय ढक्कती से पूर्ण कार्य होते रहे। संघ की असमर्थता एवं शक्तिहीनता सन् 1935-36 में इटली के इथियोपिया के आक्रमण के समय पूरी तरह प्रकट हो गई थी। यह मामला उसकी परीक्षा का प्रतीक था जिसमें वह असफल हो गया।

सामूहिक सुरक्षा के यन्त्र के रूप में राष्ट्रसंघ के प्रति मोघियत एवं अमेरिकन दृष्टिकोण

फासिस्ट शक्तियों द्वारा पैदा किए गए पौडिक वातावरण और युद्ध रूपी संकट का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रसंघ के व्यावहारिक उपायों पर सोचियन

दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रमण्डल में सोवियत प्रतिनिधि लिटविनोव (Litvinov) ने कहा था—

“एक बात के प्रति मैं बहुत स्पष्ट विचार रखता हूँ कि शान्ति और सुरक्षा, शान्दिक बचनों और घोषणाओं की बदलती हुई स्थितियों पर संगठित नहीं हो सकते। राष्ट्रों को शान्तिपूर्ण इरादों के बचनों में सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे उन्हें कितनी ही बार बयान दोहराया जाए। विशेषतया, उन स्थानों पर जहाँ आक्रमण का खतरा नजर आ रहा हो और सभी ओर से युद्ध और विजयों की घोषणाएँ हो रही हो तथा भौतिक और आध्यात्मिक आघातों पर युद्ध की तैयारियाँ की जा रही हो। हमें यह निर्णय करना चाहिए कि प्रत्येक देश को, निकटतम या दूर के पड़ोसी से सुरक्षा की गारण्टी प्राप्त करने का अधिकार हो और इस प्रकार की माँग को अविवशता की दृष्टि से न देखा जाए। वास्तव में, ईमानदार सरकारें कभी आक्रमणकारी इरादों नहीं रखती और घोषणाओं के स्थान पर ऐसी गारण्टी देने से इन्कार नहीं करती जो स्वयं उन पर लागू होती हो और साथ ही उन्हें भी पूर्ण सुरक्षा का विश्वास दिला सके।”

“मैं यह नहीं कहूँगा कि राष्ट्रमण्डल के पास शान्ति-संगठन के अवसरों और साधनों की कोई कमी नहीं थी। मैं शायद इसके साधनों की सीमाओं को आप से अधिक जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग के पास युद्ध को पूर्णतया समाप्त करने के साधन नहीं हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि सभी सदस्यों के दृढ़-निश्चय और सहयोग के द्वारा इस खतरे को टालने के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। सोवियत सरकार ने अपने पूर्ण अस्तित्व-काल में इसमें कभी रुकावट नहीं दी। यहाँ भी हम अपने प्रयत्नों को लोग के अन्य प्रतिनिधि राज्यों से मिलाने के लिए ही पहुँचे हैं।”¹

इस प्रकार लिटविनोव ने फासिस्ट आक्रमण के भावी शिकारों को सचेत कर दिया, कि यदि आज वे एकजिंत होना स्वीकार नहीं करेंगे तो शीघ्र ही उन्हें पूर्णतया बिलस जाना पड़ेगा। परन्तु समुक्त राज्य और यूरोप के बुर्जुआ राजबेत्ता अभी भी फासिस्ट उद्देश्यों के बहकावे में थे और तानाशाहों के युद्ध को स्थानीय बना देने के अभिलाषी थे।²

लिटविनोव के विपरीत राष्ट्रपति रूजवेल्ट का विचार था कि शान्ति को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। बहुत से अन्य यूरोपियन देश भी इन्हीं विचारों का समर्थन कर रहे थे। परन्तु शान्ति के विभाजन का विचार केवल एक भ्रान्ति ही था जो कि आने वाली घटनाओं से सिद्ध हो गया और हम के प्रतिनिधि का अविभाजित शान्ति पर बल दिया जाना आधारभूत गुणों से निहित विचार प्रमाणित हुआ।”

1 Quoted by Arthur Upham Pope in his biography, 'Maxim Litvinov'.

(मिश एव शत्रु : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, पृष्ठ 168-169)

2 के. के. मिश एव इन्दु शत्रु : वही, पृष्ठ 169.

तत्कालीन विश्व-राजनीति में सोवियत यथार्थवाद को दर्शाते हुए डॉ. मिश्र एवं खन्ना ने ठीक ही लिखा है, "संयुक्त राज्य के बुर्जुआ शासकों ने जहाँ तटस्थता और सिद्धान्तहीन निष्पक्षता पर बल देकर विश्व-शान्ति के प्रति विश्वासघात किया, वहाँ सोवियत दूरदर्शी नेताओं ने मध्यता के प्रति फासिस्ट संकट को दूर करने की चेष्टा की। विश्व-शान्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए सोवियत विदेश नीति फासिस्ट विरोधी लोकतन्त्रों के साथ सहयोग स्थापित करने की ओर मुवत्ती रही और राष्ट्रमध्य को सामूहिक सुरक्षा का यन्त्र बना पाने के प्रयत्न में लगी रही।"

राष्ट्रमध्य की असफलता

सामूहिक सुरक्षा के यन्त्र के रूप में राष्ट्रमध्य अन्ततोगत्वा असफल रहा है। इसका एक मुख्य कारण सदस्यों का असहमतापूर्ण दृष्टिकोण था। मार्च, 1949 में स्थापित ने कहा था कि आक्रमणकारी राज्य, मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा की नीति अर्थात् आक्रमणकारी का सामूहिक विरोध करने की नीति को त्याग दिया और असहमता तथा निरपेक्षता की नीति अपना ली। इस नीति का अर्थ था आक्रमणकारी को प्रोत्साहन देना। कनाडा का विचार है कि, जानें या अनजाने दुनिया के राज्यों ने सामूहिक सुरक्षा के माध्यम राष्ट्रमध्य के दोनों को कम करने की अपेक्षा और अधिक बढ़ाया। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सामूहिक सुरक्षा के वे फल प्राप्त न हो सके जिनकी कल्पना की गई थी। सामूहिक सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय गठन के कारण नहीं बनूँ राष्ट्रीय नीतियों के कारण असफल हो गई।"

समर वेल्लज (Summer Welles) के मतानुसार राष्ट्रमध्य समय पर कार्यवाही करने में प्रायः असफल रहा। राष्ट्रमध्य में सोवियत मध्य ने सदैव यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया और 'शक्ति अविभाजित है' के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया जबकि अन्य शक्तियों का व्यवहार सोवियत मध्य के प्रति उदासीनता अथवा उद्देश्य का रहा। ये बातें राष्ट्रमध्य की असफलता की ओर ले गईं। समर वेल्लज के ही शब्दों में—

प्रत्युत्तर में समर वेल्लज (Summer Welles) ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा "जब सोवियत मध्य ने लीग में प्रवेश किया तो बहुत तंगदिल राष्ट्रों को भी मानना पड़ा कि सोवियत सरकार ही एक ऐसी मुख्य शक्ति थी जो लीग के उद्देश्यों में विश्वास रखती थी। इसका विचार था कि लीग को प्रत्येक देश के व्यक्तिगत और स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए पदार्थ मात्र ही नहीं मानना चाहिए। लीग के सम्मेलन में सोवियत प्रतिनिधि मेक्सिम लिटविनोव को ब्रिटिश सरकार के आदेश द्वारा 'एक खतरनाक विदेशी' मानकर इंग्लैंड में आने नहीं दिया गया और सन् 1920 में जब इंग्लैंड और सोवियत मध्य की प्रथम मन्त्रि पर हस्ताक्षर हुए थे तो उसके लिए क्रसिन (Krassin) को भेजा गया था। परन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि वही मेक्सिम लिटविनोव ही केवल एक ऐसा यूरोपियन राजवंश है जो युद्ध के समय में मदद ही उचित विचार रखता रहा था। यह उसी की मन्त्रि प्रणीत थी कि शक्ति अविभाजित है और लीग के उद्देश्यों को मफलता नहीं प्राप्त हो सकती है यदि सभी यूरोपियन देश इसी के मुभाकों को स्वीकार करें। यदि यूरोप की सभी शक्तियाँ यह

ध्यान रखने के लिए तत्पर न हों कि लीग की अनुज्ञप्ति को का पालन सभी के द्वारा हो रहा है या नहीं तो निर्णय निश्चित है।”

“लिटविनोव एक स्पष्टवादी व्यक्ति है। कई बार वह उदण्ड हो जाता है परन्तु मेरे विचार में वह कभी कुटिल नहीं था। जब तक लीग में वह अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करता रहा, उसने अपनी पूरी योग्यता से लीग के कार्यों को सम्पन्न करवाने का प्रयत्न किया। यह ध्यान में रखना चाहिए कि सोवियत सरकार ने लीग का परित्याग नहीं किया। लीग के अन्तिम वर्षों में इस पर शासन कर रही कुछ महान् शक्तियाँ थी जिन्होंने सोवियत सघ का परित्याग किया हुआ था।

“सन् 1931 में जापान ने निर्णय किया था एशियाई क्षेत्र पर उनके आधिपत्य स्थापित करने का उचित समय आ गया है, तो क्षितिज में फिर से अन्धकार के बादल छा गए। तीन मन्चूरियन क्षेत्रों पर जापान द्वारा बलात्कार, और साधारण डिट दिए जाने पर लीग से स्वाग-पत्र दे देने का जापान का निर्णय, समस्याओं से लीग का साक्षात्कार करवा रहा था। इंग्लैंड की बाल्डविन (Baldwin) सरकार ने बले पर आधारित कोई भी कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया। अतः जर्मनी और इटली में बढ़ती हुई शक्तियों को ध्यान में रखकर उन्हें चेतावनी दे दी गई थी कि इस वैश्विक संकट के समय में राष्ट्रसंघ स्वयं को अयोग्य पा रहा है।”

लीग द्वारा इस समय कोई कार्यवाही न किया जाना हो, इथोपिया (Ethiopia) पर मुसोलिनी के आक्रमण, स्पेन में फासिज्म की विजय और हिटलर के ‘महान् जर्मनी’ निर्माण के निर्णय का मुख्य कारण था। कोई भी निर्णय इतना घातक सिद्ध नहीं हुआ होगा जितना कि सन् 1932 में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का लीग की समाप्त कर देने का था।

“कुछ ही वर्षों में जनता और सरकारें तीव्र गति में चलती हुई घटनाओं में घिर चुकी थी और दुःसन्त परिणाम की ओर जा रही थी। परन्तु अभी भी पश्चिमी लोकतन्त्रों के बहुत से नेता इस गहाव की गति को समझ नहीं पा रहे थे कि यह मानवता को कहाँ लिए जा रहा है।”¹

सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्रसंघ
(Collective Security and the U. N. O.)

राष्ट्रसंघ की भाँति ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधान में भी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और यह अपने पूर्ववर्ती की प्रपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। “संयुक्त राष्ट्रसंघ के पास अब दाँत हैं, यदि वे प्राकृतिक दाँत नहीं हैं तो कम से कम बने हुए दाँत अवश्य हैं” और यदि वे हमेशा अच्छी तरह प्रयोग में न लाए जा सकें तो भी कम से कम उनमें काटने की शक्ति तो है ही।²

1 पिप एव थ्रॉ से उद्धृत : वही, पृष्ठ 169-70.

2 Andrew Martin : Collective Security, p. 135.

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि शान्ति-स्थापना के लिए, जब जैसी आवश्यकता हो तब सदस्य-राष्ट्र सुरक्षा-परिषद् की सहायता के लिए अपनी सशस्त्र सेनाएँ, सहायता और अन्य सुविधाएँ जिनमें भाग-अधिकार भी शामिल होंगे, सुरक्षा परिषद् को जुटाएँगे। यह भी प्रावधान है कि सदस्य सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय वायु-सेना को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएँगे ताकि संयुक्त राष्ट्रसंघ तुरन्त सैनिक कार्यवाही कर सके। यद्यपि शान्ति स्थापित रखना सुरक्षा-परिषद् का प्रथम उत्तरदायित्व है, तथापि 'शान्ति के लिए एकता' (Uniting for Peace) के प्रस्ताव द्वारा यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि यदि कभी शान्ति के लिए संकट पैदा हो जाए अथवा शान्ति भंग हो, अथवा आक्रमण हो जाए और सुरक्षा-परिषद् पारस्परिक मतभेदों के कारण इस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन न कर सके, तो महासभा अपना संकटकालीन अधिवेशन बुलाकर तुरन्त मामला अपने हाथ में ले सकती है और स्थिति कामुकाबला करने के लिए सामूहिक कार्यवाही का सुझाव दे सकती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की परीक्षा का अवसर पहली बार सन् 1950 में आया था जब दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया के आक्रमण के मामले को राष्ट्रसंघ ने अपने हाथ में लिया। कोरिया-युद्ध में यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभावशाली सैनिक विरोध न करता तो सम्भव था कि तृतीय महायुद्ध का विस्फोट हो जाता। कुछ विचारकों का मत है कि कोरिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्यवाही के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया। सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था के अनुसार होना यह चाहिए था कि आक्रमणकारी को राजा देने अथवा उसका प्रतिरोध करने के लिए किसी भी आक्रमणकारी के विरुद्ध कड़ी भी लड़ा जाता, किन्तु इसके स्थान पर सामूहिक शक्ति का प्रयोग केवल अमेरिका के प्रबल शत्रु के विरुद्ध किया गया था। जो भी हो कोरिया-युद्ध ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को कुछ अनुभव प्रदान किए तथा सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया।

सन् 1956 में महासभा के संकटकालीन अधिवेशन में अविस्मर्य युद्ध-विराम पर बल दिया गया और प्रस्ताव पास किया गया कि महासचिव मिस्त्र में युद्ध बन्द करने तथा युद्ध-विराम की देखभाल करने के लिए संघ की एक आपात्कालीन सेना (UNEF) का गठन करें किन्तु 15 नवम्बर को आपात्कालीन सेना का पहला दस्ता मिस्त्र पहुँचने से पहले ही 6-7 नवम्बर की मध्य रात्रि में ब्रिटिश-फ्रांसीसी सैनिक कार्यवाही बन्द कर दी गई थी। स्वेज-विवाद की संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यवाही सामूहिक सुरक्षा की सफलता थी यह संदिग्ध है। वास्तव में कुछ अन्य कारणों से आक्रमणकारियों ने महासभा के आदेशों का पालन किया था जिनमें मोचित हस्तक्षेप की चेतावनी प्रमुख थी।

वास्तव में कोरिया-युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को कार्यान्वित करने

में संयुक्त राष्ट्रगंध पीछे ही हटा। संयुक्त राष्ट्रगंध सामूहिक सुरक्षा के अपने उत्तर-दायित्वों को सच्चे अर्थों में नहीं निभा सका है—इसे इंगित करते हुए पामर एवं पकिंस ने यहाँ तक लिख दिया है कि “अनुभव है आधार पर यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रवृत्ति के कारण वास्तविक सामूहिक सुरक्षा का न तो कभी प्रभावशाली साधन था और न भविष्य में कभी हो सकता है।” सुरक्षा-परिपद में महाशक्तियों के नियेधाधिकार ने एक ऐसी व्यूह-रचना कर दी है जिसमें चूहों को तो कुचला जा सकता है, निन्तु शेरों को नहीं रोका जा सकता। नियेधाधिकार ने सामान्य सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है। अब तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के सम्पूर्ण लेसे-जोसे का मूल्यांकन करने पर वैच विच तथा मार्टिन के इन शब्दों से असहमत होना कठिन है कि “संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर ने सामूहिक सुरक्षा की प्रवास्तविक पद्धति स्थापित की है।”

सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय सन्धियाँ

(Collective Security and Regional Pacts)

विश्व के दो गुटों में बँट जाने से सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था का भाग्य चन्द्र-राह के समान सिद्ध हुआ। शीतयुद्ध के दाव-पेचों तथा घेरेबन्दी के परिणामस्वरूप साम्यवादी और पूँजीवादी गुटों द्वारा सन्धि-संगठनों का निर्माण किया जाने लगा। विचारकों के एक पक्ष की यह मान्यता है कि इन क्षेत्रीय संगठनों के आधार पर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाया जा सकता है तो दूसरे पक्ष वालों का मत है कि सन्धियों का आधार गुटबन्दी होता है और इन्हें कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये शक्ति और सुरक्षा को नहीं बल्कि युद्ध की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। इनके विचार में क्षेत्रीय सन्धियों अथवा प्रादेशिक संगठनों और समझौतों से ग्राम खाने की करपना करना आकाश-कुसुम की भाँति निराधार और मृग-मरीचिका की भाँति भ्रामक है।

क्षेत्रीय सन्धियों को चाहे घनेक राजनीतिज्ञों और शान्तिवादियों ने अनुचित बताया, लेकिन इनका विकास होता ही गया। द्वितीय महायुद्ध के मध्यवर्ती काल में क्षेत्रीय संगठनों और समझौतों का बड़ी संख्या में निर्माण किया गया। बहुत कुछ इन्हीं के कारण राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा की स्थापना में प्रसफल हुआ और वह उन राज्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका जिन्होंने आक्रामक रूप धारण कर लिया था।

जब द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्तराष्ट्रसंघ की स्थापना हुई तो उसके चार्टर में भी प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय संगठनों और समझौतों सम्बन्धी उपबन्ध रहे गए। वस्तुतः अधिकांश अमेरिकी और पश्चिमी राजनीतिज्ञों तथा सैन्य-विशारदों के लिए यह चिन्ता का विषय था कि ‘रूसी दानव’ यूरोप में ‘लोह आवरण’ (Iron Curtain) के पूर्व में उद्गड़तापूर्वक विचार रहा था और उसका प्रभाव सारे यूरोप पर पड़ रहा था। पामर और पकिंस ने लिखा है—“यह तो अनुमान लगाने की बात थी कि रूसी सेनाएँ कुछ ही दिनों, सप्ताहों अथवा महीनों में इंगलिश चैनल तथा

अटलांटिक सागर तक पहुँच सकती है अथवा नहीं परन्तु यह निश्चित था कि 'पूर्व' (अर्थात् रूस) की ओर से हवाई आक्रमण के मार्ग में कोई भौगोलिक अथवा सैनिक बाधाएँ नहीं थी।"

चूँकि राजनीतिज्ञों का बहुमत और अधिकांश राज्य यह नहीं चाहते थे कि आक्रमण के समय संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् के 5 स्थायी सदस्यों के हाथ में ही कार्यवाही करने का अधिकार रहे, अतः उन्होंने अपनी भावी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के सिद्धान्त का समर्थन किया और इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में उपयुक्त व्यवस्था की।

यद्यपि संयुक्तराष्ट्रसंघ के चार्टर की व्यवस्थाओं में यही घोषणा की गई कि क्षेत्रीय संगठन और समझौते विश्व-संगठन के उद्देश्यों का परित्याग न करते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होंगे, परन्तु विश्व की महाशक्तियों ने इस आड में अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करने का खेल खेला। परिणामतः विगत 15-20 वर्षों में क्षेत्रीय सन्धियों और संगठनों की बाढ़ सी आ चुकी है जिनसे विश्व-शान्ति और सामूहिक सुरक्षा की समस्या सुलझाने के स्थान पर उत्पन्न रही है। इन संगठनों और समझौतों ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ उत्पन्न की हैं, तनाव को बढ़ाया है और संयुक्तराष्ट्रसंघ के महत्त्व को घटाया है। कुछ प्रमुख प्रादेशिक संगठन और समझौते (Regional Alliances) ये हैं—ब्रूसेल्स सन्धि संगठन, 'नाटो', वारसा पैक्ट, केन्द्रीय सन्धि संगठन (सैंटो), दक्षिण-पूर्वी-एशिया-सन्धि संगठन (सीटो) आदि। वस्तुतः क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक सन्धियों और संगठनों का भ्रम सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की अपेक्षा शक्ति-सन्तुलन के विचार के अधिक निकट है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सम्बन्धित अनुच्छेद
(Relevant Articles of the U. N. Charter)

संयुक्त राष्ट्रसंघ में सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय या प्रादेशिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जिन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का प्रावधान है उनके अवलोकन से संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को समझने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि चार्टर के अनुच्छेदों में 'सामूहिक सुरक्षा' नाम प्रयुक्त न होकर 'सामूहिक प्रयत्नों या उपायों' (Collective Measures) तथा 'सामूहिक कार्यवाही' (Collective Action) शब्दावलिओं का प्रयोग हुआ है। नीचे जो अनुच्छेद दिए जा रहे हैं¹ उनमें अनुच्छेद 1 (1) अध्याय एक का है, अनुच्छेद 39 से लेकर 51 अध्याय सात के हैं और अनुच्छेद 52 से 54 अध्याय आठ हैं। अध्याय सात 'शान्ति के प्रति धमकियों, शान्ति-भंग की स्थितियों तथा आक्रमण के विषय में कार्यवाही' (Action with Respect of Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression) से सम्बन्धित है और अध्याय आठ 'क्षेत्रीय या प्रादेशिक व्यवस्था' (Regional Arrangements) से सम्बन्धित है।

1 हव मार्गेशो : 'राष्ट्रों के मध्य राजनीति' के उद्धृत, पृष्ठ 682-687.

अनुच्छेद 1 (1)—अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना और इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्नो (Collective Measures) द्वारा शान्ति के संकटों को रोकना और समाप्त करना, तथा आक्रमण की एक शान्ति-भंग की अन्य चेष्टाओं को दबाना, तथा न्याय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा उन अन्तर्राष्ट्रीय विवादों अथवा स्थितियों को सुलझाना अथवा निपटारा करना, जिनसे शान्ति-भंग होने की आशंका हो।

अनुच्छेद 39—सुरक्षा-परिषद् यह निर्णय करेगी कि शान्ति को घमकी दी गई है, शान्ति भंग हुई है अथवा आक्रमण हुआ है, तथा वह सिफारिशें करेगी और निश्चित करेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाए रखने अथवा पुनः स्थापित करने के लिए 41 एवं 42 अनुच्छेदों के अनुसार क्या कार्यवाहियाँ (Measures) की जाएँगी।

अनुच्छेद 40—किसी स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए अनुच्छेद 39 में उल्लिखित सिफारिशें करने और कार्यवाहियों (Measures) के विषय में निर्णय करने के पूर्व सुरक्षा-परिषद् विवादी पक्षों से ऐसी अस्थायी कार्यवाहियों का अनुपालन करने को कह सकती है जिन्हें वह उचित अथवा आवश्यक समझती हो। ऐसी अस्थायी कार्यवाहियों से सम्बन्धित विवादी पक्षों के अधिकारों, दावों एवं स्थितियों का कोई अहित नहीं होगा। यदि कोई विवादी पक्ष इन अस्थायी कार्यवाहियों (Provisional Measures) का अनुपालन नहीं करता तो सुरक्षा-परिषद् इसकी ओर भी विधिवत् ध्यान देगी।

अनुच्छेद 41—सुरक्षा-परिषद् अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी कार्यवाहियों (Measures) के विषय में भी निर्णय कर सकती है जिनमें सशस्त्र बल का प्रयोग न हो और वह समुक्त-राष्ट्रसंघ के सदस्यों को इन कार्यवाहियों का अनुपालन करने के लिए कह सकती है। इन कार्यवाहियों के अनुसार आर्थिक सम्बन्धों तथा रेल, समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो एवं संचार-व्यवस्था के अन्य साधनों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रोका जा सकता है और राजनयिक सम्बन्ध भी तोड़े जा सकते हैं।

अनुच्छेद 42—यदि सुरक्षा-परिषद् यह समझे कि अनुच्छेद 41 में उल्लिखित कार्यवाहियाँ (Measures) अपर्याप्त होगी अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाए रखने अथवा पुनः स्थापित करने के लिए सुरक्षा-परिषद् वायु, समुद्र अथवा स्थल सेनाओं की सहायता से आवश्यक कार्यवाही (Action) कर सकती है।

अनुच्छेद 43—1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखने में सहयोग देने के लिए समुक्तराष्ट्र के सब सदस्य यह उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित रखने के उद्देश्य से वे सुरक्षा-परिषद् के मार्गों पर तथा विशेष समझौतों के अनुसार अपनी सशस्त्र सेनाएँ, सहायता एवं सुविधाएँ, जिनमें मार्ग-अधिकार भी सम्मिलित हैं, प्रदान करेंगे।

2. ऐसा समझीता अथवा समझीते सेनाओं की संख्या एवं प्रकार, तैयारी एवं सामान्य स्थिति की कोटि तथा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सहायता के स्वरूप को निश्चित करेंगे।

3. सुरक्षा-परिषद् की प्रेरणा से ऐसा समझीता अथवा समझीते जितने शीघ्र सम्भव हो वार्ता द्वारा किए जाएंगे। ये समझीते सुरक्षा-परिषद् एवं सदस्यों अथवा सुरक्षा-परिषद् एवं सदस्यों के समूहों के बीच होंगे तथा हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की अपनी-अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार सत्यापन के पश्चात् लागू होंगे।

अनुच्छेद 44—जब सुरक्षा-परिषद् ने सैनिक कार्यवाही करने का (To use Force) निर्णय किया हो, तो वह किसी ऐसे सदस्य से, अनुच्छेद 43 के अधीन उत्तरदायित्व की पूर्ति के हेतु सशस्त्र सेनाएँ माँगने के पहले, जिसका सुरक्षा-परिषद् में प्रतिनिधित्व नहीं है, उस सदस्य की इच्छानुसार उसे सुरक्षा-परिषद् के उन निर्णयों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित कर सकती है जिनका उस सदस्य की सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग से सम्बन्ध हो।

अनुच्छेद 45—संयुक्त राष्ट्रसंघ को शीघ्र सैनिक कार्यवाही (Military Measures) करने योग्य बनाने के लिए सदस्य सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्तन के कार्य के लिए तुरन्त राष्ट्रीय वायु-सेना की सुलभ टुकड़ियाँ तैनात करेंगे। इन टुकड़ियों की शक्ति और तत्परता की मात्रा तथा इनकी सामूहिक क्रिया की योजना 'सैनिक-स्टॉफ-समिति' की सहायता से सुरक्षा-परिषद् द्वारा अनुच्छेद 43 में उल्लिखित विशेष समझीते या समझीतों की सीमाओं के अन्तर्गत निर्धारित होगी।

अनुच्छेद 46—सुरक्षा-परिषद् सैनिक स्टॉफ समिति की सहायता से सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग के लिए योजनाएँ बनाएगी।

अनुच्छेद 47—1 एक सैनिक स्टॉफ समिति स्थापित की जाएगी जो सुरक्षा-परिषद् को उन सभी प्रश्नों पर परामर्श एवं सहायता देगी जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा-परिषद् की सैनिक आवश्यकताओं, उसके अधीन सेनाओं के प्रयोग एवं कमान, शस्त्रों के नियन्त्रण और सम्भावित निःशस्त्रीकरण से हो।

2. सैनिक-स्टॉफ समिति में सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों के 'स्टॉफ' के अध्यक्ष (चीफ ऑफ स्टॉफ) अथवा उनके प्रतिनिधि होंगे। यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य का इस समिति में स्थायी रूप से प्रतिनिधित्व न हो और समिति के दायित्वों की निपुणतापूर्वक पूर्ति के लिए समिति के कार्य में उस सदस्य का भाग लेना आवश्यक हो तो, समिति उसे अपने साथ काम करने के लिए आमन्त्रित करेगी।

3. सुरक्षा-परिषद् के अधीन रह कर सैनिक स्टॉफ समिति उन सशस्त्र सेनाओं के युद्ध सम्बन्धी निर्देशन के लिए उत्तरदायी होगी जो सुरक्षा-परिषद् के उपयोग के लिए इसे दी जाएँगी। इन सेनाओं के कमान सम्बन्धी प्रश्न बाद में निश्चित किए जाएंगे।

4. सुरक्षा-परिषद् से अधिकार प्राप्त होने पर और उपयुक्त प्रादेशिक संस्थाओं के साथ परामर्श के पश्चात् सैनिक स्टॉफ-समिति प्रादेशिक उप-समितियाँ भी स्थापित कर सकती है।

अनुच्छेद 48—1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखने के हेतु सुरक्षा-परिषद् के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए जो कार्यवाही आवश्यक होगी, उसके विषय में सुरक्षा-परिषद् निर्धारित करेगी कि वह संयुक्तराष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा हो अथवा उनमें से कुछ के द्वारा।

2. संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य स्वतन्त्र रूप से तथा जिन उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के वे सदस्य हैं उनमें अपनी कार्यवाही द्वारा इन निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे।

अनुच्छेद 49—सुरक्षा-परिषद् द्वारा निर्धारित कार्यवाही को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य एक-दूसरे को सहयोग देंगे।

अनुच्छेद 50—यदि सुरक्षा-परिषद् द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध निवारक अथवा प्रवर्तन-सम्बन्धी कार्यवाही हो रही हो और किसी अन्य राज्य के समक्ष, जो संयुक्त-राज्य का सदस्य हो अथवा नहीं, इस कार्यवाही के लागू होने के कारण विशेष आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँ, तो उसे इन समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में सुरक्षा-परिषद् से परामर्श करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 51—यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई सशस्त्र आक्रमण हो तो उसे व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से आत्मरक्षा का अन्तर्निहित अधिकार है; और जब तक सुरक्षा-परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही (Measures) नहीं करती, तब तक वर्तमान चार्टर के अनुसार इस अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। आत्म-रक्षा के इस अधिकार के प्रयोग में सदस्य जो भी कार्यवाही (Measures) करेंगे, उनकी सूचना तत्काल सुरक्षा-परिषद् को दी जाएगी और इस कार्यवाही का सुरक्षा-परिषद् की वर्तमान चार्टर के अधीन उस शक्ति एवं उत्तरदायित्व पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसके अनुसार वह किसी भी समय अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित रखने अथवा पुनः स्थापित करने के लिए ऐसी कार्यवाही (Action) कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

अनुच्छेद 52—1. ऐसे प्रादेशिक प्रबन्ध एवं संस्थाओं के अस्तित्व में, जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के बने रहने से सम्बन्धित मामलों पर विचार करते हैं और उपयुक्त प्रादेशिक कार्यवाही करते हैं, वर्तमान चार्टर के अनुसार कोई बाधा नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि ऐसे प्रबन्ध अथवा संस्थाएँ तथा उनके कार्य संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुरूप हों।

2. संयुक्त राष्ट्र के वे सदस्य जो ऐसी व्यवस्थाओं के भी सदस्य हैं अथवा ऐसी संस्थाओं का निर्माण करते हैं, स्थायी विवादों को सुरक्षा-परिषद् के समक्ष ले

जाने के पहले ऐसे प्रादेशिक-प्रबन्धों अथवा ऐसी प्रादेशिक-संस्थाओं द्वारा उनका शान्तिपूर्ण निपटारा करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करेगे।

3. सुरक्षा-परिषद् राज्यों के अभिक्रम द्वारा अथवा स्वयं ही स्थानीय विवादों के इन प्रादेशिक प्रबन्धों अथवा इन प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए प्रोत्साहन देगी।

4. इस अनुच्छेद से अनुच्छेद 34 एवं 35 के लागू होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 53—1 जहाँ उचित होगा, सुरक्षा-परिषद् अपने अधिकार में इन प्रादेशिक प्रबन्धों अथवा संस्थाओं का प्रवर्तन-सम्बन्धी कार्यवाही में उपयोग करेगी। परन्तु इन प्रादेशिक प्रबन्धों अथवा प्रादेशिक संस्थाओं के अधीन तब तक कोई प्रवर्तन-सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक सुरक्षा-परिषद् इसका अधिकार न दे। ये उन कार्यवाहियों के विषय में अपवाद हैं जो किसी शत्रु-राज्य के विरुद्ध जिसकी परिभाषा इस अनुच्छेद के पैरा 2 में की गई है, अनुच्छेद 107 के अनुसार अथवा किसी ऐसे राज्य के पुनः प्राक्रमणकारी नीति के अपनाने के विरुद्ध तब तक की जा रही हो जब तक सम्बन्धित राष्ट्रों के निवेदक पर उस राज्य के द्वारा आगे प्राप्त होने के लिए सगठन को इसका उत्तरदायित्व न दिया जाए।

2 इस अनुच्छेद के पैरा 1 में जो 'शत्रु राज्य' शब्द का प्रयोग किया गया है, वह उस राज्य के लिए लागू होता है जो दूसरे महायुद्ध में इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले किसी राष्ट्र का शत्रु रहा है।

अनुच्छेद 54—प्रादेशिक प्रबन्धों अथवा प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के सपोषण के लिए जो कार्यवाही की जाएगी अथवा जिस कार्यवाही पर विचार हो रहा होगा, उसकी पूर्ण सूचना सुरक्षा-परिषद् को समय-समय पर दी जाएगी।

सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था का मूल्यांकन

(An Evaluation of Collective Security System)

सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था, चाहे वह किसी भी रूप तथा आकार में हो, तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक कि उसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त शक्ति उपलब्ध न हो। शक्ति के बिना किसी भी दमनकारी प्राप्तिकरण को कुचला नहीं जा सकता। सामूहिक सुरक्षा की वाध्यकारी शक्ति के रूप के नैदानिक दृष्टि से तीन विकल्प हो सकते हैं—

1. सदस्य राज्यों द्वारा सहयोग का वचन दिया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सैनिक शक्तियों के प्रयोग करने का वायदा भी दिया जा सकता है।

2. राज्य अपनी सेना के कुछ भाग अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के पास छोड़ देंगे ताकि वह सामूहिक सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर काम में ला सकें।

3. अन्तर्राष्ट्रीय संघ अपनी स्वयं की सेना का अलग से निर्माण करे तथा वह सेना सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करे।

राष्ट्रसंघ द्वारा प्रथम विकल्प को अपनाया गया था। राष्ट्रसंघ में किस विकल्प को अपनाया जाए इस सम्बन्ध में बहुत समय तक भारी वाद-विवाद रहा, अन्त में कुछ देशों की पूरी सहमति न रहते हुए भी द्वितीय विकल्प को अपना लिया गया। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को आज की परिस्थितियों में अव्यावहारिक, अमम्भव तथा निष्फल माना जाता है। इस पक्ष के समर्थन में प्रायः निम्न तर्क दिए जाते हैं—

1. आक्रमणकारी जब आक्रमण करता है तो वह पूरी तैयारी और सोच-विचार के साथ करता है और जिस देश पर आक्रमण किया जाता है उसकी प्रतिक्रिया भी तत्काल ही होती है—वहाँ पूरी सैनिक तैयारी की जाएगी, सकेटकालीन बजट पास किया जाएगा तथा परिस्थितियों के अनुकूल जो भी आवश्यक होगा किया जाएगा, किन्तु सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की इकाइयों को पूरी तरह यह पता नहीं रहना कि कहीं, किमके विरुद्ध, कब किसके साथ मिलकर सैनिक कार्यवाही करनी चाहिए और इसी कारण तत्कालीन सामूहिक युद्ध कठिन हो जाता है। फलतः सामूहिक सुरक्षा समुदाय की सैनिक शक्ति उसके किसी भाग से सदैव कम होगी।

2. सन् 1945 ई. के बाद सैनिक तकनीक में भारी परिवर्तन आ गया है। वैज्ञानिक विकास के कारण आज के युद्ध ऐसे बन चुके हैं कि आक्रमणकारी के विरुद्ध कदम उठाने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था विचार करने का प्रबन्ध करे तब तक आक्रमणकारी देश को नष्ट कर देगा। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र यह जानता है कि वह अपने जीवन और मरण का प्रश्न सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं छोड़ सकता, इसका उसे स्वयं ही प्रबन्ध करना होगा।

3. विश्व का दो गुटों में बँट जाना (Bipolarity) भी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के विपरीत सिद्ध हुआ है। सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था यह मानती है कि उसके प्रतिबन्धों का प्रभाव प्रत्येक देश पर पड़ेगा और कोई भी देश आक्रमण करने का साहस न कर सकेगा। किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कम व अमेरिका की नई शक्ति का जिस रूप में उदय हुआ है उस पर सामूहिक सुरक्षा के प्रतिबन्धों का कोई प्रभाव होने जाने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त दो गुटों की व्यवस्था में यह भी एक बाधा होती है कि आक्रमणकारी राज्य किसी भी एक गुट के सदस्य या नेता होते हैं और इस कारण उस गुट के दूसरे सदस्य-राज्य सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं होने देते।

4. सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि आक्रमणकारी तथा जिस पर आक्रमण किया गया है उस देश को स्पष्ट रूप से घेरे और दबा दिया जाए क्योंकि बिना इसके कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। भारत-पाक संघर्ष के समय भारत द्वारा बराबर यह माँग की गई कि वह पाकिस्तान को आक्रमक घेरे, किन्तु ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वह घोषणा जितनी सरल दीखती थी

उतनी नहीं थी, इसमें अनेक राष्ट्रों के हित टकराते थे। आक्रमण की परिभाषा एवं अर्थ भी अनेक लगाए जाते हैं। पहले तो यही पता लगाया जाए कि अमुक कार्यवाही आक्रमण है या नहीं, यदि है भी, तो आक्रमणकारी कौन है ?

5. सामूहिक सुरक्षा की सफलता की विषयगत परिस्थितियाँ बढ़ने की अपेक्षा धीरे-धीरे घटती जा रही हैं। जिस समय इस सिद्धान्त को अपनाया जा सकता था उस समय राजनीतिज्ञों का ध्यान इसकी तरफ नहीं था। जब वे इसे क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो बाह्य परिस्थितियाँ ऐसा नहीं करने देती। विषयगत आवश्यकताओं (Subject Requirements) को देखकर ऐसा लगता है कि यह सिद्धान्त अपरिपक्व है क्योंकि न तो राजनीतिज्ञ और न ही जनता इसकी पूर्ण आवश्यकताओं से परिचित होते हैं आज के युग में ऐसे समुदाय का विकास हो गया है जो अपने-अपने राष्ट्रीय हित के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और इसी कारण उसमें भिन्नता है। इस समय सामूहिक सुरक्षा की सफल क्रियान्विति यह माँग करती है कि ऐसे राजनीतिज्ञ हों जो नेतृत्व कर सकें और ऐसी जनता हो जो उनका अनुगमन कर सके। इस विचार का विकास किया जाए कि जो विश्व के लिए शुभ है वही राज्य के लिए भी शुभ है। राष्ट्रीय हित को विश्व-शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ एकरूप कर दिया जाए। क्लाड (Claude) का मत है कि "सक्रिय सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की पूर्ण आवश्यकताएँ पूर्ण होने से अभी बहुत दूर हैं और यह भी सदिग्ध है कि इस दिशा में कुछ अर्धपूर्ण विकास हो सकेगा।"

6. जिस व्यक्ति के हाथों में विदेश-नीति के संचालन का भार रहता है वह सदैव व्यावहारिक नीति को अपनाएगा तथा प्रत्येक मामले को गौर से देखने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। वह केवल सिद्धान्तों के पीछे न दौड़ेगा। कोई भी राजनीतिज्ञ यह पसन्द नहीं करेगा कि वह सामूहिक सुरक्षा जैसे किसी भी सिद्धान्त की जजीरो में अपने हाथों को जकड़ कर कुछ करने के लिए अपने आपको विवश कर ले। एक सफल राजनीतिज्ञ वही है जिसके सामने घनेक विषयों के द्वार खुले रहते हैं और परिस्थिति के अनुकूल मार्ग अपनाने में उनके सामने कोई बाधा नहीं आती। दूसरे शब्दों में आज की दुनिया के लोग यह विश्वास नहीं करते कि सामूहिक सुरक्षा के साधन द्वारा विश्व-व्यवस्था (World Order) या राष्ट्रीय हित प्राप्त किया जा सकता है।

7. मॉर्गेंथो आदि विचारकों की मान्यता है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत युद्ध का क्षेत्र सीमित या स्थानीय न रहकर विश्वव्यापी बन जाता है। जिस युद्ध के परिणामों को एक क्षेत्र-विशेष तक ही सीमित किया जा सकता था, वे विश्व युद्ध विध्वंस की भाग में भौंक देते हैं। एक देश यदि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अर्थों में आक्रमणकारी के विरुद्ध अभ्यन्त्रित देश का साथ दे रहा है तो भी यह समझा जाएगा कि ऐसा वह अपने स्वार्थ-साधन के लिए कर रहा है। दूसरी ओर कुछ विचारक यह मानते हैं कि विश्व में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडलान्तिक नीति के बजाय व्यावहारिक नीति की आवश्यकता होती है। क्लाड (Claude) का निष्कर्ष है कि सामूहिक सुरक्षा शक्ति की दृष्टि से अयथार्थ नहीं है वरन् यह नीति की ओर से अयथार्थ है।

सामूहिक सुरक्षा का आदर्श स्वरूप : डॉ. नायडू के विचार
(The Ideal Typology of Collective Security :
Dr. Naidu's Views)

सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था के समापन से पूर्व यह उचित होगा कि डॉ. एम. बी. नायडू के उन विचारों की जानकारी प्राप्त कर ली जाए जो उन्होंने सामूहिक सुरक्षा के आदर्श स्वरूप तथा सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की पूर्ण शर्तों (The Ideal Typology of Collective Security and the Pre-requisites for a System of Collective Security) के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए हैं। ब्रैडन विश्वविद्यालय, कनाडा में राजनीति विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष डॉ. एम. बी. नायडू ने सन् 1974 में प्रकाशित अपनी बहुचर्चित पुस्तक (Collective Security and the United Nations) में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण और परम्परा से भिन्न अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है और पुस्तक के अन्तिम अध्याय में सामूहिक सुरक्षा के आदर्श स्वरूप और इसकी पूर्व-शर्तों का उल्लेख किया है।¹ पहले हम स्वरूप को ले रहे हैं और तत्पश्चात् पूर्व-शर्तों का उल्लेख करेंगे।

डॉ. नायडू के अनुसार सामूहिक सुरक्षा के आदर्श स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित सात तत्वों (Seven Elements) के आधार पर किया जा सकता है—

1. सैनिक शक्ति के स्वेच्छाचारी या मनमाने प्रयोग का निषेध (Prohibition of Arbitrary Use of Military Force) अर्थात् राज्यों द्वारा शक्ति का निरवुश और आत्मपरक प्रयोग (Arbitrary and Subjective Use of Force) किन्हीं भी परिस्थितियों में अव्याज्य है।

2. सुरक्षा की सामूहिक गारन्टी (Collective Guarantee of Security) अर्थात् सुरक्षा की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 'एक सब के लिए और सब एक के लिए' (One for all, all for one) के सिद्धान्त पर आधारित हो सकती है और होनी भी चाहिए।

3. निरोध और अनुशास्ति के रूप में सामूहिक सेना (Collective Force as Deterrence and Sanction) अर्थात् सभी राज्यों की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय सेना किसी भी सम्भावित आक्रमणकारी का निरोध करेगी। यदि किसी आक्रमण का निरोध न किया जा सके तो सामूहिक सेना एक अनुशास्ति के रूप में क्रियाशील होगी जो आक्रमण को रोक देगी, समाप्त कर देगी अथवा अभिशून्य कर देगी (Will Stop, End or Vacate the Aggression)।

4. सामूहिक कार्यवाही का स्वचालित होना (Automation of Collective Action) अर्थात् कोई भी आक्रमण होने पर सामूहिक कार्यवाही की मशीनरी स्वतः-चालित हो जाएगी और यह कार्यवाही तेजी से और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए।

5 आक्रान्ता और आक्रान्त की अनामकता (Anonymity of the Aggressor and Victim) अर्थात् सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह बिना किसी पक्षपात या द्वेष आदि के आक्रान्त की निन्दा करे (Condemns any Aggressor) और आक्रान्ता की सहायता करे (Will help any victim state) ।

6. अपराध का निश्चय या निर्धारण (Assignability of Guilt) अर्थात् सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए जिसमें आक्रमण की परिभाषा दी गई हो, आक्रान्ता को पहचानने की प्रक्रिया दी गई हो और उन संस्थाओं का उल्लेख हो जो इन प्रक्रियाओं को तेजी और निष्पक्षता के साथ परिभाषित और लागू कर सकें ।

7. व्यवस्था का स्थायित्व और सामान्य स्वरूप (Permanency and Generality of the System) अर्थात् सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था स्थाई नींव पर टिकी होनी चाहिए, सामान्य प्रयोग और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए ।

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की पूर्व-शर्तें
(The Pre-requisites for a System of Collective Security)

डॉ. नायडू ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ पूर्व-शर्तों (Pre-requisites) का उल्लेख किया है जो अग्रलिखित हैं—

1. व्यक्ति के विवेक और उसकी भलमनसाहत में विश्वास (Faith in the Rationality and Goodness of Man) अर्थात् सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में सलग्न व्यक्तियों का विश्वास इस सिद्धान्त में होना चाहिए कि शारीरिक शक्ति का प्रयोग अविवेकपूर्ण और अनैतिक दोनों ही है ।

2 विश्व-समुदाय में विश्वास (Faith in World Community) अर्थात् राज्यों को मनुष्य के भाईचारे में आस्था होनी चाहिए । उन्हें यह सोचकर कार्य करना चाहिए कि जो विश्व-समुदाय के लिए शुभ है वही राष्ट्रीय समुदाय के लिए शुभ है ।

3. शान्ति की अविभाज्यता में विश्वास (Faith in the Indivisibility of Peace) अर्थात् विश्व के किसी भी भाग अथवा किसी भी राज्य में संपर्प, अन्याय और युद्ध को अपने स्वयं के राज्य की शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा समझा जाना चाहिए क्योंकि किसी भी स्थान पर होने वाला अनियन्त्रित आक्रमण कालान्तर में विश्व के दूसरे राज्यों को प्रभावित करता है ।

4 व्यवस्था की निष्पक्षता में विश्वास (Faith in the Impartiality of the System) अर्थात् सदस्य-राज्यों को व्यवस्था की वास्तविकता और निष्पक्षता में विश्वास रखना चाहिए । इस विश्वास के अभाव में व्यवस्था प्रभावी नहीं बन सकेगी ।

5. सामूहिक गारण्टियों में विश्वास (Faith in Collective Guarantees) अर्थात् प्रत्येक राज्य को न केवल व्यवस्था के निर्णयों और उसकी शुभकामना में विश्वास रखना चाहिए बल्कि व्यवस्था के सभी प्रयत्नों को अपना समर्थन देना चाहिए। सभी के लिए सुरक्षा की गारण्टी के रूप में व्यवस्था की विश्वसनीयता में आस्था का होना आवश्यक है।

6. यथापूर्व-स्थिति में विश्वास (Faith in the Status-quo) अर्थात् सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था राज्यों की वर्तमान राजनीतिक सम्प्रभुता और प्रादेशिक एकता कायम रखने और उसकी रक्षा करने का बचन देती है। अधिकारों, दोषों और न्याय की जो अवधारणाएँ वर्तमान में प्रचलित हैं उन्हें वह कायम रखने का वचन देती है। दूसरे शब्दों में, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यथापूर्व-स्थिति (Status-quo) के माध्यम से शान्ति को पक्षधर है।

7. विसर्पित शक्ति वाता विश्व (A World of Diffused Power) अर्थात् यदि एक या कुछ राज्यों में शक्ति केन्द्रित है तो बड़ी शक्तियाँ इतनी हावी हो जाएंगी कि शेष छोटे राज्य उन पर इस दृष्टि से कोई अकुश नहीं रख सकेंगे कि वे उन्हें तंग न करें। यदि निष्पत्तीकरण या शस्त्रास्त्र नियन्त्रण सम्भव होना तो सामूहिक सुरक्षा अधिक प्रभावी हो सकती थी। शक्ति-गुट (Power Blocks) सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन नहीं देते।

8. सदस्यता की विश्व-व्यापकता (Universality of Membership) अर्थात् सभी या कम से कम अधिकांश राज्यों को (बड़ी शक्तियों सहित) सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था का सदस्य होना चाहिए अथवा सामूहिक सुरक्षा का कोई भी प्रयास केवल बहु-पक्षीय सन्धि या क्षेत्रीय सुरक्षा-व्यवस्था बन कर रह जायगा। यदि बड़ी शक्तियाँ व्यवस्था से बाहर रहनी हैं तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अपना प्रभाव खो देगी।

9. सम्प्रत्यय और प्रक्रिया की वैधानिकता (Legality of Concept and Procedure) अर्थात् प्रभावशाली रूप में कार्य करने के लिए व्यवस्था को वैधानिक और वस्तुगत सम्प्रत्ययों और प्रक्रियाओं तथा निष्पक्ष सरयाओं से सम्पन्न होना चाहिए ताकि राजनीति की मनमानी नहरे, शीतयुद्ध के राग-द्वेष और राष्ट्रीय प्रतिवद्धता की अनिश्चितताएँ सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की कार्यशीलता को बाधित, मितम्बित अथवा पेचीदा न बनाएँ।

10. विश्व-सरकार के सादृश्य (Approximation to World Government) अर्थात् सामूहिक सम्प्रभुता (Collective Sovereignty) के अभाव में सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था में परिणत होती है जो विश्व-समुदाय, विश्व-विधि, विश्व राजनीति और विश्व-शान्ति अर्थात् संक्षेप में एक विश्व-सरकार पर आधारित हो।

क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा की एक व्यवस्था है ? : डॉ. नायडू के विचार

(Is the U. N. a System of Collective Security ? :

Dr. Naidu's Views)

डॉ. नायडू ने विश्व के बुद्धिजीवियों से प्रश्न किया है कि क्या सामूहिक सुरक्षा के आदर्श स्वरूप के पूर्वोक्त सात तत्त्व किसी भी समकालीन बहुपक्षीय या क्षेत्रीय सन्धि अथवा संगठन में मौजूद है। जिसे सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था का नाम दिया हो, उदाहरणार्थ क्या ये तत्त्व NATO, WTO, SEATO, OAS, GAU आदि सन्धि-संगठनों में पाए जाते हैं। डॉ. नायडू के अनुसार इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हो सकता है अर्थात् 'नहीं' ('No')। डॉ. नायडू का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ की सुरक्षा-व्यवस्था को भी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की संज्ञा देना भ्रामक है। उसे सामूहिक व्यवस्था (System of Collective Measures) कहना अधिक उपयुक्त होगा।¹ डॉ. नायडू के अनुसार संघ के चार्टर में जिस सुरक्षा-व्यवस्था का प्रावधान किया गया है उसे अनुच्छेद 1 (1) और विशेषकर अध्याय 7 में 'सामूहिक उपाय' (Collective Measures) अथवा सामूहिक कार्यवाही (Collective Action) कहा गया है। अनुच्छेद 39, 40, 41, 45, 49, 50, 51 और 53 में 'उपाय' (Measures) शब्द का प्रयोग हुआ है जबकि अनुच्छेद 42, 48, 51 और 53 में कार्यवाही (Action) शब्द का प्रयोग किया गया है (इस प्रकार कुछ अनुच्छेदों में 'प्रयत्न' और 'कार्यवाही' दोनों शब्दावलिियाँ प्रयुक्त हुई हैं)। चार्टर में कहीं भी 'सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था' (Collective Security System) शब्दों का उल्लेख नहीं है।

भारत और सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त

(India and the Principle of Collective Security)

स्वतन्त्र भारत आदर्शवादी और भौतिक दोनों ही कारणों से शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक है। जैसा कि प्रो. मसलदान ने लिखा है, "आक्रमण रोकने और शान्ति को प्रोत्साहन देने के लिए भारत का सामूहिक सुरक्षा के आदर्श में विश्वास है।"² भारत के स्वाधीन होने से पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) ने भारतीय संविधान सभा में ये शब्द कहे थे—

"हम शान्ति चाहते हैं। यदि हमारा वश चले तो हम किसी भी राष्ट्र से युद्ध नहीं करना चाहते। दूसरे राष्ट्रों के साथ मिल कर कार्य करने से हमारा एकमात्र

1 "The U. N. security system, provided in the Charter and evolved through the experiments and the precedents of the U. N. may be identified as the system of collective measures." —M. V. Naidu : op. cit., 1974, p. 101.

2 "It believes in the ideal of Collective Security for the prevention of aggression and the promotion of peace."

—P. N. Masaldan : 'Collective Security'—an article in the book, 'Studies in World Order,' 1972, edited by Harnam Singh, p. 325.

सम्भव वास्तविक उद्देश्य यह हो सकता है कि हम किसी प्रकार की विश्व-संरचना (World Structure) के निर्माण के लिए सहयोग करें। इसे आप चाहे तो एक विश्व की संज्ञा दे सकते हैं या कोई और नाम दे सकते हैं। इस विश्व-संरचना का प्रारम्भ संयुक्त राष्ट्रमण्डल के रूप में हो चुका है। यह अभी तक बमजोर है तथा इसमें अनेक दोष हैं, तथापि हममें सन्देह नहीं कि यह एक विश्व-संरचना की शुरुवात है और भारत में इसके कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा की है।¹

एक सामूहिक सुरक्षा संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्रमण्डल के प्रति भारत का दृष्टिकोण इस प्रकार के तत्वों से प्रभावित रहा है—शान्ति की प्रमुखता, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित रखने के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त के रूप में महा-शक्ति सामञ्जस्य (Great-power Harmony) की आवश्यकता में दृढ़ विश्वास, जिस तरीके से संयुक्त-राष्ट्रमण्डल ने अभी तक के विवादों को (कश्मीर विवाद सहित) निपटाने के प्रयत्न किए हैं उसका अनुभव, आदि।² भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्रमण्डल स्वयं को केवल अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास से सम्बन्धित रखे, क्योंकि यह वह सर्वोत्तम तरीका है जिसके द्वारा शान्ति के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सकता है। भारत का भी विचार है कि संयुक्त राष्ट्रमण्डल की सफलता के लिए आवश्यक आधारशिला के रूप में महाशक्ति सामञ्जस्य होना चाहिए। अपने इन विश्वासों और विचारों के कारण यह स्वाभाविक है कि भारत सामूहिक सुरक्षा संगठन के हेतु उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राथमिकता दे।

प्रो मसलदान ने ठीक ही लिखा है कि यद्यपि भारत का संयुक्त राष्ट्रमण्डल में पूरा विश्वास रहा है, लेकिन जिस ढंग से इस विश्व-संस्था ने अब तक कार्य किया है उससे वह प्रसन्न नहीं है। भारत यह महसूस करता रहा है कि यह संगठन महाशक्तियों के शीत-युद्ध से बहुत अधिक प्रभावित है और अनेक अवसरों पर यह शीत-युद्ध की राजनीति का अस्व (Cold-War Politics) बन गया है जिसके परिणामस्वरूप यह बहुत-से विवादों पर न्यायपूर्ण ढंग से न विचार कर सका है और न निर्णय दे सका है। इसके विचार और निर्णय महाशक्तियों के शीतयुद्ध की रणनीति की नांगो के अनुसार रहे हैं। यही कारण है कि भारत संयुक्त राष्ट्रमण्डल को शक्तों से सुसज्जित करने के प्रस्ताव के प्रति उदासीन है। आज जो अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बना हुआ है उसमें इस बात की आशंका है कि महाशक्तियाँ शान्ति के नाम पर सैनिक रूप से सबल संयुक्त राष्ट्रमण्डल को अपने नापाक इरादों की पूर्ति का साधन बनाएँगी। सन् 1951 में कोरिया युद्ध के समय भारत ने चीन को आक्रान्ता घोषित करने के प्रस्ताव का विरोध किया था क्योंकि भारत को आशंका थी कि इस प्रकार का कोई भी कार्य शान्ति-स्थापना में नही बल्कि संघर्ष के विस्तार में सहयोगी होगा। भारत का इस प्रकार का दृष्टिकोण भविष्य में अल्पनियतवा कहां तक सही और

1 Jawaharlal Nehru : India's Foreign Policy, 1961, p. 11.

—Quoted by P. N. Masaldan : Ibid, p. 325.

2 P. N. Masaldan : Ibid, p. 325.

विवेकपूर्ण सिद्ध होगा, यह नहीं कहा जा सकता, तथापि जैसा कि प्रो. मसलदान ने लिखा है, यह आवश्यक है कि यदि किसी सुरक्षा-संगठन को सदस्य-राष्ट्रों का विश्वास और सम्मान अर्जित करना है तो उसके आग्रमण के अपराधी प्रत्येक राष्ट्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी होगी, फिर उसे तात्कालिक परिणाम चाहे जो निवर्त्ते। भारत की नाराजगी का यह बिल्कुल सही कारण है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने पाकिस्तान को उस समय भी आश्रान्ता घोषित नहीं किया जब यह सुस्थापित तथ्य माना जा चुका था कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था। संयुक्त राष्ट्रसंघ का यह पक्षपातपूर्ण रवैया इसीलिए रहा क्योंकि पश्चिमी शक्तियों का रुचि विवाद के निष्पक्ष मूल्यांकन में नहीं थी—पाकिस्तान उनके साथ कुछ सैनिक सन्धियों में बँधा था, भारत नहीं।

भारत की गुट-निरपेक्ष नीति की एक आधारभूत मान्यता यह है कि सैनिक गुट तनावों में अभिवृद्धि कर शान्ति की सम्भावनाओं को नष्ट करते हैं। यही कारण है कि जहाँ भारत सुरक्षा के लिए एक विश्व-संगठन को प्रोत्साहित और स्वागत योग्य मानता है, जहाँ क्षेत्रीय सैनिक सन्धियों का विरोध करता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्रीय सन्धियाँ सुरक्षा या मानव की दृष्टि से किसी लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। ये सन्धियाँ विश्व-संगठन के महत्त्व को भी ठेस पहुँचाती हैं। प्रो. मसलदान का मत है कि विश्व-संगठन के ढाँचे में क्षेत्रीय प्रबन्ध यदि समुचित रूप से कार्यशील रहते हैं तो भारत के विरोध का औचित्य कुछ सन्देहास्पद हो जायेगा। शान्ति और सुरक्षा की समस्या के प्रति भारत का अपना दृष्टिकोण है और वह विश्व-संस्था के साथ सहयोग के पक्ष में है, लेकिन यदि विश्व-संस्था महाशक्तियों के हाथों का खिलौना बन जाए तो भारत का क्षोभ और विरोध अस्वाभाविक नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समझौते (Peaceful Settlements of International Disputes)

ताशवन्द वार्ता के लिए मास्को रवाना होने से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री शास्त्री ने एक आमसभा में कहा था कि “कोई भी देश हमेशा युद्ध करता हुआ नहीं रह सकता। युद्ध को एक न एक दिन बन्द होना ही पड़ता है। युद्ध द्वारा किसी भी समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता, इससे नई समस्याओं का निर्माण जरूर किया जा सकता है।”

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे के बीच बाँधी सम्बन्ध है। सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में समस्या को सुलझाने के साधन के रूप में युद्ध या शक्ति का सहारा तभी लिया जाता है जब अन्य साधन असफल हो जाते हैं। प्रारम्भ में तो यह प्रयोग किया जाता है कि आग्रमण से प्रभावित राष्ट्र तथा आग्रमण करने वाले राष्ट्र के बीच समझौते, शान्ति-वार्ता एवं अन्य मित्रतापूर्ण माधनो से मेल करा दिया जाए, किन्तु जब ऐसा सम्भव न हो सके तब अन्त में मजबूर होकर शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। शान्तिपूर्ण समझौते की सम्भावना तथा उनकी सफलता की सम्भावना केवल तभी रहती है जब दोनों पक्षों के बीच

तुल्यभारिता (Equilibrium) या शक्ति-सन्तुलन की स्थिति वर्तमान हो। जैसा सन्धियों जैसे शान्तिपूर्ण साधनों से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का प्रयत्न बहुत समय से ही प्रचलित है। शक्ति का महत्त्व शान्तिपूर्ण समझौतों की संकल्पना के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जैसे कोई भी न्यायालय का निर्णय तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकता जब तक कि पुलिस शक्ति उस निर्णय को प्रियान्वित कराने में सक्षम सहयोग न दे, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन देशों के शब्दों का प्रभाव अधिक होता है जो कि शक्तिशाली हैं तथा निर्णय का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र को जिन्हें कुछ खतरा हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे की दिशा में अब तक पर्याप्त विकास हो चुका है। उदाहरण के लिए सन् 1899 का हेग सम्मेलन, राष्ट्रसंघ स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय, सन् 1924 का जेनेवा सन्धि क्षेत्र तथा समुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर आदि की गणना की जा सकती है।

शान्तिपूर्ण समझौतों को दो श्रेणियाँ (Two Categories of Pacific Settlement)

शान्तिपूर्ण समझौतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—निर्णायक (Decisional) तथा गैर-निर्णायक (Non-decisional)। गैर-निर्णायक शान्ति-समझौता वह माना जाता है जो ऐसा कोई सुझाव नहीं देता जिसे अन्तिम रूप से दोनों ही पक्ष मानने को विवश हों। ऐसे समझौतों में बातचीत (Negotiation), मेल-मिलाप (Conciliation), आदि साधनों द्वारा जित निर्णयों अथवा निर्णयों पर पहुँचा जाता है उनको मानने या न मानने के लिए दोनों ही पक्ष स्वतन्त्र रहते हैं। निर्णायक (Decisional) समझौते वे होते हैं जिनके निर्णयों का पालन करने के लिए दोनों ही पक्ष बाध्य होते हैं। पचायत (Arbitration) तथा न्यायीकरण (Adjudication) आदि साधनों द्वारा इस प्रकार के समझौतों तक पहुँचा जाता है। यह व्यवस्था है कि दोनों ही पक्ष अपने भगदों को इन व्यवस्थाओं के सुपुर्द कर दें या करने में स्वतन्त्र हैं, किन्तु सुपुर्द करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि वे उस पचायत अथवा न्यायीकरण के निर्णयों को मानें। कुछ विचारकों के मत में उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी में यह माँग बड़ी है कि राजनीतिक तथा कानूनी मामलों को निर्णायक प्रक्रियाओं के सुपुर्द किया जाए, किन्तु समस्या यह है कि राजनीतिक या वैधानिक भगदें क्या होती हैं तथा इनको सुलझाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया (न्यायीकरण या पचायत व्यवस्था) का स्वरूप कैसा होना चाहिए।

शान्तिपूर्ण समझौतों के साधन (Methods for Peaceful Settlements)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अध्याय 6 में अनुच्छेद 33 से 38 तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाएँ दी गई हैं। मूल अनुच्छेद इस प्रकार है—

अनुच्छेद 33—1. यदि किसी विवाद के स्थायित्व से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रहने में संकट की सम्भावना हो तो विवादी पक्ष सर्वप्रथम उस विवाद का समाधान वार्ता, जाँच, मध्यस्थता, भेल-मिलाप, विवाचन, न्यायिक निपटारा, प्रादेशिक मस्याओ अथवा व्यवस्थाओ की सहायता अथवा अपनी इच्छानुसार अन्य शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा करने का प्रयत्न करेगा।

2 सुरक्षा-परिषद् आवश्यकतानुसार विवादी पक्षों को अपने विवादों का इन साधनों द्वारा निपटारा करने का परामर्श देगी।

अनुच्छेद 34—सुरक्षा-परिषद् किसी विवाद की अथवा किसी ऐसी स्थिति की, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय संधि अथवा विवाद होने की आशंका हो, इस अभिप्राय से जाँच कर सकती है कि उस विवाद अथवा स्थिति के स्थायित्व से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रहने में संकट की सम्भावना है अथवा नहीं।

अनुच्छेद 35—1 संयुक्त राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य ऐसे विवाद अथवा ऐसी स्थिति की ओर सुरक्षा-परिषद् अथवा महासभा का ध्यान आकर्षित कर सकता है जिसका अनुच्छेद 34 में उल्लेख किया गया है।

2. यदि एक राज्य संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है तो वह किसी विवाद को, जिसमें वह विवादी पक्ष है, इस शर्त पर सुरक्षा-परिषद् अथवा महासभा के समक्ष ला सकता है कि उस विवाद के लिए वह वर्तमान चार्टर में उल्लिखित शान्तिपूर्ण निपटारे के दायित्वों को अग्रिम रूप से स्वीकार करे।

3. इस अनुच्छेद के अनुसार जिन मामलों को महासभा के समक्ष लाया जाएगा, उनसे सम्बन्धित उसकी कार्यवाहियाँ अनुच्छेद 11 एवं 12 के उपबन्धों के अधीन होंगी।

अनुच्छेद 36—1 यदि कोई विवाद इस प्रकार का हो जिसका अनुच्छेद 33 में उल्लेख किया गया है अथवा उसी प्रकार की स्थिति हो, तो सुरक्षा-परिषद् किसी भी समय समायोजन के लिए उचित प्रक्रियाओ अथवा उपायों की सिफारिश कर सकती है।

2. सुरक्षा-परिषद् उन प्रक्रियाओ का भी ध्यान रखेगी जिनका विवाद के निपटारे के हेतु विवादी पक्षों द्वारा पहले प्रयोग किया जा चुका है।

3. इस अनुच्छेद के अन्तर्गत सिफारिशें करते हुए सुरक्षा-परिषद् को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि साधारणतया कानूनी विवाद, विवादी पक्षों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष उस न्यायालय की संविधि के उपबन्धों के अनुसार पेश किए जाएँ।

अनुच्छेद 37—1. यदि विवादी पक्ष किसी ऐसे विवाद का, जिसका अनुच्छेद 33 में उल्लेख किया गया है, उस अनुच्छेद में संकेत किए हुए साधनों द्वारा निपटारा करने में असफल हो, तब उन्हें उस विवाद को सुरक्षा-परिषद् के समक्ष रखना होगा।

2. यदि सुरक्षा-परिषद् यह समझे कि किसी विवाद के स्थायित्व से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए संकट की सम्भावना है, तब वह निर्णय करेगी कि अनुच्छेद 36 के अधीन कार्यवाही की जाए अथवा समझौते के लिए ऐसी शर्तों की सिफारिश की जाए जिन्हें वह उचित समझती है।

अनुच्छेद 38—यदि किसी विवाद के सभी विवादी पक्ष निवेदन करें तो सुरक्षा-परिषद् 33 से 37 तक के अनुच्छेदों के उपबन्धों का उल्लंघन किए बिना विवाद का शान्तिपूर्ण निपटारा करने के अभिप्राय से सिफारिशें कर सकती हैं।

अनुच्छेद 38 से स्पष्ट है कि यदि किसी विवाद से विश्व-शान्ति और सुरक्षा को खतरा हो और सम्बन्धित पक्ष अपना भगड़ा स्वयं निपटाने में असफल रहे तो सुरक्षा परिषद् विवादी से वार्ता (Negotiation), जाँच (Enquiry) मध्यस्थता (Mediation), सराफन (Conciliation), पक्ष-निर्णय (Arbitration), न्यायिक समझौतों (Judicial Decisions), प्रादेशिक संस्थाओं या व्यवस्थाओं (Regional Agencies or Arrangements) अथवा अपनी इच्छानुसार शान्तिपूर्ण उपायों (Other Peaceful Means of their own choice) द्वारा विवाद के निपटारे की सिफारिश कर सकता है। यहाँ विवादों के शान्तिपूर्ण समाधानों पर कुछ विस्तार से उल्लेख आवश्यक है।

वार्ता (Negotiation)—यह कूटनीतिक (Diplomacy) साधन है। मैथेमेटिक्स पैलेस्टाइन कन्वेंशन के विवाद के प्रसंग में न्यायाधीश मूर ने कहा था, "अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में वार्ता एक वैधानिक, व्यवस्थित तथा प्रशासनात्मक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से राज्य-सरकारें अपनी सन्दिग्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के साथ अपने सम्बन्धों का मंचालन करती हैं और मतभेदों पर विचार-विमर्श, उनका व्यवस्थापन तथा समाधान करती हैं।" विवाद के समाधानार्थ, विवादी पक्षों के बीच वार्ता या तो शीर्षस्थ स्तर पर सीधे राजपाक्षों द्वारा की जाती है अथवा उनके द्वारा नियुक्त या अधिकृत अधिकर्ताओं द्वारा। विवाद के समाधान की दृष्टि से दो पक्षों के बीच होने वाले पत्र-व्यवहार को भी वार्ता का ही अंग माना जाता है। इस प्रक्रिया का आधार कोई विशेष कानूनी उत्तरदायित्व न होकर व्यावहारिक सुविधा होती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 'मल्पसूर्यको की समस्या' और 'नहरी-गानी विवाद' को वार्ता द्वारा ही सुलझाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की उदारता का कोई आदर नहीं किया। वास्तव में 'वार्ता' के उपाय की सफलता दोनों पक्षों द्वारा समस्याओं के समाधान की लगन और ईमानदारी पर निर्भर है।

वाद-विवाद (Discussion)—सुरक्षा परिषद् अथवा महासभा, जो भी सिफारिश करने से पूर्व विवादी पक्षों के प्रतिनिधियों को लिखित या मौखिक रूप से अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित करती है और इस प्रकार उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहाँ वे स्वतन्त्र रूप से अपनी शिकायतें रखते हैं तथा द्विपक्षीय

कूटनीति (Bilateral Diplomacy) के माध्यम से ऐसी स्थिति में पहुँच सकते हैं जहाँ विवाद के समाधानमें कोई समझौता हो सके। यह भी सम्भव है कि विवादी पक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय मंच का उपयोग केवल विश्व-जनमत को अपने अनुकूल करने की दृष्टि से करें अथवा दोनों पक्षों के बीच मतभेदों की खाई पूर्वापेक्षा अधिक चौड़ी हो जाए। इस बात की भी पूर्ण आशंका रहती है कि विवाद (Dispute) कूटनीतिक दावपेचों और राजनीतिक वाद-विवाद के भँवर में फँसकर शीत-युद्ध का अंग बन जाए और लम्बे असें तक चलता रहे जैसा कि कश्मीर-विवाद।

सद्भावी सेवा एवं मध्यस्थता (Good Offices & Mediation)—जब विवादयुक्त पक्ष समझौता-वार्ता द्वारा अपने मतभेदों को नहीं सुलझाना चाहते या इस कार्य में असफल हो जाते हैं तो तीसरा मित्र-राज्य अपनी सद्भावी सेवा या मध्यस्थता द्वारा इन मतभेदों को मित्रतापूर्ण तरीके से दूर करने में मदद कर सकता है। तीसरा राज्य अपने प्रभाव द्वारा सेवा-कार्य को सम्भालता है और दोनों पक्षों के बीच शान्ति-पूर्ण समझौता करा देता है। सद्भावी सेवा (Good Offices) का प्रयोगकर्ता राज्य विवाद के दोनों पक्षों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखता है।

सद्भावी सेवा और मध्यस्थता के बीच केवल मात्रा का अन्तर है सद्भावी सेवा में तीसरा राज्य दोनों पक्षों को एक साथ बैठाता है और विवाद को सुलझाने के लिए सुझाव देता है, किन्तु इस समय तीसरा राज्य वास्तविक समझौता-वार्ता में भाग नहीं लेता। मध्यस्थता के समय हस्तक्षेपकर्ता राष्ट्र वार्ता में स्वयं भाग लेता है। वह अपनी ओर से सुझाव देता है और विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से सम्बद्ध लेता है। मध्यस्थ प्रस्ताव को मानना या न मानना दोनों पक्षों की इच्छा पर निर्भर करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जब तीसरे राज्य की ओर से दो राज्यों के विवादों को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया गया है। कभी-कभी यह हस्तक्षेप सशस्त्र सेनाओं द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने वाला राज्य विवाद में एक नया तत्त्व जोड़ देता है। दूसरी ओर हस्तक्षेप मित्रतापूर्ण एवं दबावकारी प्रकृति का होता है। इनमें दोनों पक्षों को विवाद मिटाने के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं जिनको स्वीकार करने या न करने की स्वतन्त्रता होती है।

मध्यस्थता करने-वाला राज्य विवादग्रस्त राज्यों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करता है और विरोधी दावों में समन्वय स्थापित करता है। कई बार वह युद्ध की सम्भावनाओं को भी दूर करता है। सद्भावी सेवा या मध्यस्थता करने वाले पक्ष एक व्यक्ति या कोई अन्तर्राष्ट्रीय निकाय भी हो सकता है।

प्लानो एव रिग्न का बयन है कि विवाद के समाधान की प्रक्रियाओं हेतु जो सिफारिशें सुरक्षा परिषद् या महासभा द्वारा की जाती हैं उनमें अधिकारियों के उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय पुनर्वार्ताएँ, गलाह-मशिवरा, मिनी मयुक्त राष्ट्रीय आयोग द्वारा जाँच एवं मध्यस्थता, समुक्त राष्ट्रमधीन विनी प्रनिनिधि या मध्यस्थ की नियुक्ति,

किसी क्षेत्रीय अभिकरण को निर्देशित करना, पंच-निर्णय, न्यायिक निर्णय कराना, आदि सम्मिलित हैं।

मेलमिलाप या संराधन (Conciliation)—विवादों के निपटारे का यह एक अन्य साधन है। इसमें वे विभिन्न प्रणालियाँ शामिल हैं जो तीसरे पक्ष द्वारा दो या अधिक राज्यों के विवादों को शान्तिपूर्वक हल करने के लिए अपनायी जाती हैं। प्रो. ओपेनहीम के अनुसार, "यह विवाद के समाधान की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह कार्य कुछ व्यक्तियों के आयोग को सौंप दिया जाता है। यह आयोग दोनों पक्षों का विवरण सुनता है तथा तथ्यों के प्रकाश में विवाद को तय करने की दृष्टि से अपना प्रतिवेदन देता है। इसमें विवाद के समाधानार्थ कुछ प्रस्ताव होते हैं। ये प्रस्ताव किसी पंचाट या अदालती निर्णय की भाँति अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होते।"

संराधन और मध्यस्थता के बीच अन्तर है। प्रथम के अन्तर्गत दोनों पक्ष अपना विवाद अन्य व्यक्तियों को इसलिए सौंपते हैं ताकि वे तथ्यों की निष्पक्ष जाँच के बाद विवाद के समाधान के प्रस्ताव उपस्थित करें। यहाँ पहल विवादी पक्षों द्वारा की जाती है। मध्यस्थता में पहलकर्ता तीसरा राज्य ही होता है। यह स्वयं विवाद के पक्षों के बीच बातों चलाकर विवाद को हल करना चाहता है।

जाँच (Enquiry)—सुरक्षा परिषद् किसी ऐसे भगड़े अथवा स्थिति की जाँच-पड़ताल कर सकती है जिसके अन्तर्राष्ट्रीय मध्य का रूप लेने की सम्भावना हो अथवा जिससे कोई दूसरा भगड़ा उठ सकता हो सकता हो। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ मेलमिलाप एवं जाँच आयोग के माध्यम से अनेक सगरमाथी को सुलभाने की चेष्टा करती रही हैं। उदाहरण के लिए सन् 1931 में मन्चूरिया काण्ड के लिए राष्ट्रसंघ ने लिटन आयोग नियुक्त किया था। इण्डोनेशियाई और कश्मीर-विवाद में भी राष्ट्रसंघीय आयोगों ने बड़ी अमूल्य भूमिका प्रदा की थी।

पंच-निर्णय (Arbitration)—वार्ता, मध्यस्थता, संराधन, जाँच आदि जो उपाय हैं उन्हें प्रायः निर्णायक (Non-Decisional) उपाय कहा जाता है क्योंकि विवादी पक्ष इस बात के लिए बाध्य नहीं होते कि वे इन उपायों द्वारा प्रस्तुत सुझावों अथवा निर्णयों को स्वीकार करें। इन्हें प्रभावकारी बनाने के लिए कुछ अन्य उपाय खोजे गए हैं जिनके निर्णयों को दोनों पक्षों द्वारा मान्यता आवश्यक होता है। ये निर्णयात्मक उपाय मुख्यतः दो हैं—पंच-निर्णय तथा न्यायिक निर्णय अथवा अधिनियम।

पंच-निर्णय का अर्थ अनेक विचारकों तथा राजनीतिज्ञों द्वारा समय-समय पर दिया गया है। प्रो. ओपेनहीम लिखते हैं—“पंच-निर्णय का अर्थ है कि राज्यों के मतभेदों का समाधान कानूनी निर्णय द्वारा किया जाए। यह निर्णय दोनों पक्षों द्वारा निर्वाचित एक या अनेक पंचों के न्यायिकरण द्वारा होता है जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न प्रकृति का है।” पंच-निर्णय का कार्य या तो किसी ऐसे राज्याध्यक्ष को सौंपा जा सकता है जो गैर-न्यायिक अथवा कानून की जानकारी न रखने वाला व्यक्ति हो या किसी न्यायाधिकरण को।

न्यायिक समाधान (Judicial Settlement)—विवादों का न्यायिक समाधान अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से होता है। न्यायालय के फैसले के अनुसार यदि कोई विवादपक्ष अपने दायित्व को पूर्ण न करे तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद् का आश्रय ले सकता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य स्वतः ही अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के सदस्य बन जाते हैं। इनके अनिर्दिष्ट दूसरे राज्य भी बिना इसका सदस्य बने कोई एक पक्ष बन सकते हैं। यद्यपि न्यायालय आवश्यक और सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार नहीं होता, तथापि इसके निर्णय उन पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं जो इस न्यायाधिकरण को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं।

मध्यस्थ या प्रतिनिधि (Mediator or Representative)—कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिनके समाधान में सुरक्षा-परिषद्, महासभा अथवा आयोग की अपेक्षा कोई अकेला व्यक्ति मध्यस्थ या प्रतिनिधि के रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। किसी तटस्थ सभा-स्थल पर अथवा विपक्षी दलों की राजधानियों में या विवाद-स्थल पर विवाद के समाधान अथवा मतभेदों को कम करने या मिटाने की दिशा में संयुक्त-राष्ट्रसंघीय मध्यस्थ अथवा प्रतिनिधि ने अपनी महती उपयोगिता सिद्ध की है।

अवरोधक कूटनीति (Preventive Diplomacy)—अवरोधक कूटनीति का उपाय शान्तिपूर्ण समाधान का पूरक है जिसका उद्देश्य विवाद में तनाव को कम करना तथा स्थिति को बिगड़ने से रोकना होता है। प्लानों एवं रिम्ज में संयुक्त-राष्ट्रसंघ द्वारा अपनाए जाने वाले अवरोधक कूटनीति के उपायों को मोटे रूप में चार श्रेणियों में बांटा है—(1) निरीक्षक ग्रुप जो युद्ध-विराम विसंन्यीकृत क्षेत्र तथा अस्थायी युद्ध-विराम रेखाओं या सन्धि-सीमाओं का निरीक्षण करते हैं, (2) युद्धरत पक्षों के मध्य रखी गई संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ, (3) आन्तरिक संघर्ष का दमन करने और घरेलू-व्यवस्था बनाए रखने में प्रयुक्त की जाने वाली संयुक्तराष्ट्रीय सेनाएँ, तथा (4) साम्प्रदायिक समूहों में सशस्त्र संघर्ष को रोकने या सीमित करने में प्रयुक्त संयुक्तराष्ट्रीय फौजें।

अपने सीमित साधनों और परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा राष्ट्रों के प्रमुखता-सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए अभी तक अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं जिनमें से बहुतों में उसे सफलता मिली है, किन्तु महाशक्तियों की अड्डेबाजी तथा सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक अखाड़ेबाजी के कारण अनेक बार उसे असफल भी होना पड़ा है।

**एक सुधरी हुई व्यवस्था की ओर
(Towards An Improved System)**

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कुछ मुख्य दोष हैं। कुछ विवाद अनमूर्त रहकर शान्ति के लिए निरन्तर खतरा बने रह सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर और बाहर की विभिन्न कूटनीतिक प्रक्रियाएँ यद्यपि तृतीय पक्ष के प्रभाव के लिए बाकी क्षेत्र प्रस्तुत करती हैं और विभिन्न मात्रा में दबाव डालती हैं, तथापि इन

सब प्रयत्नों के बावजूद यह सम्भव है कि सम्बन्धित पक्ष किसी हल प्रथवा समाधान पर सहमत न हों। तृतीयपक्षीय समझौता या समाधान (A Third-party Settlement) तभी सम्भव होता है जब सम्बन्धित पक्ष ऐसे समझौते के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य हों और इस दिशा में वर्तमान अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक क्षेत्र बहुत ही सीमित है। तृतीय पक्ष के निर्णयों को लागू करने के लिए आज जो भी संस्थात्मक साधन सुलभ हैं वे भी बहुत सीमित हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय सुझाए गए हैं जिनमें से कुछ की परीक्षा डॉ. बी. एस. मूरिन ने अपने तर्कपूर्ण लेख 'Peaceful Settlement of Disputes' में निम्नानुसार की है¹—

कानून का संहिताकरण और विकास (Codification and Development of Law)—इस शताब्दी के प्रारम्भ में एक सुझाव यह दिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अधिक निश्चित और विस्तृत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि तभी न्यायिक व्यवस्था भली प्रकार कार्य कर सकेगी और विवादों के तृतीय पक्ष का न्यायिक समाधान (Third-party Judicial Settlement) अधिक स्वीकार्य हो सकेगा। इस सुझाव के अनुपालन में राष्ट्रसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण का प्रयत्न किया और यह प्रयत्न संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा आज भी जारी है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि-आयोग (The International Law Commission) महासभा द्वारा निर्मित यह सहायक अंग (Subsidiary Organ) है जिसका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण और उसके क्रमिक विकास को प्रोत्साहन देना है।

एक विश्व व्यवस्थापिका (A World Legislative)—लेकिन सभी कानूनों को एक संहिता (Code) में सम्मिलित नहीं किया जा सकता क्योंकि कानूनों में निरन्तर परिवर्तन होते रहना आवश्यक है ताकि वे समुदाय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी बन सकें। यह कार्य भली प्रकार तब सम्भव हो सकता है जब न्यायपालिका द्वारा संहिता की व्याख्या की एक प्रक्रिया (A Process of Interpretation of the Code by the Judiciary) कायम की जाए। लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया से केवल लघु परिवर्तन ही प्रभावित हो सकते हैं, भारी या बड़े परिवर्तन सम्भव नहीं हो सकते क्योंकि यदि न्यायपालिका ने बड़े परिवर्तन करना आरम्भ किया तो निर्णयों का महत्व घट जाएगा और न्यायिक प्रतिष्ठा के प्रति सन्देह पैदा हो जाएगा। अधिकांश व्यक्ति यह नहीं चाहेंगे कि कानून-निर्माण जैसा कार्य न्यायाधीशों के एक छोटे-से समूह द्वारा किया जाए। अतः यह सुझाव दिया गया है कि न्यायिक निर्णयों को अधिक ग्राह्य और स्वीकार्य बनाने के लिए विश्व-समुदाय की विधायी (The Legislative System of the World Committee) को सुधारना जाना चाहिए अर्थात् हमें एक विश्व-व्यवस्थापिका की दिशा में सोचना चाहिए।

1 B. S. Murin : 'Peaceful Settlement of Disputes'—an article published in the book 'Studies in World Order', edited by Harnam Singh, pp. 293-297.

एक निष्पक्ष या साम्य न्यायाधिकरण (An Equity Tribunal)—कुछ लोग राजनीतिक प्रकृति के विवादों को सुलझाने के लिए एक साम्य या निष्पक्ष न्यायाधिकरण (An Equity Tribunal) की स्थापना का सुझाव देते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा न्यायाधिकरण प्रत्येक विवाद का निपटारा कर सकेगा और विवादग्रस्त पक्षों की विशिष्ट परिस्थितियों में 'न्याय' की स्थापना कर सकेगा। अपने कार्य-निष्पादन में यह न्यायाधिकरण प्रचलित वैधानिक नियमों (The Legal Rules in Force) की लकीर का फकीर नहीं होगा बल्कि अपने विवेक से कार्य कर सकेगा। यह भी तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार के न्यायाधिकरण से उम आपत्ति का भी निराकरण हो जाएगा जो 'राजनीतिक विवादों' को तृतीय पक्षीय रुमभौते के लिए सौंपने पर की जाती है।

विवादों का प्रावरण (Encapsulation of Disputes)—एक विलुप्त भिन्न दृष्टिकोण से यह सुझाव दिया जाना है कि जब कभी दो राज्यों के बीच विवाद उठे तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझौते या समाधान का नहीं बल्कि उसके प्रावरण (Encapsulation) का होना चाहिए अर्थात् सम्बन्धित पक्षों को बाध्य किया जाना चाहिए कि वे हिंसा और संपर्क का आश्रय लेने से बचें और शान्तिपूर्ण समाधान सम्बन्धी नियमों का अनुसरण करें। यदि इस प्रकार उन्हें बाध्य किया गया तो विवाद शान्ति के लिए खतरा नहीं बन सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो लम्बे समय तक अनसुलझे रह सकते हैं और उनके सुलझाने की सम्भावना प्रायः तभी बनती है जबकि अनुवृत्त परिस्थितियाँ पैदा हो जाएँ। अतः यदि विवादों के प्रावरण (Encapsulation of Disputes) सम्बन्धी कदम उठाए जाएँ अर्थात् सम्बन्धित पक्षों को हिंसा की जगह समझौतावादी रण बनाए रखने के लिए विवश किया जाए तो लम्बे समय तक बने रहने वाले ये विवाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए 'विस्फोटक' नहीं बन सकेंगे। विवादों के प्रावरण के लिए यह आवश्यक है कि निःशस्त्रीकरण जैसे उपाय अपनाए जाएँ और हिंसा या शक्ति के किसी अर्धैधानिक प्रयोग की सम्भावना को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनित-शक्ति को संगठित किया जाए।

क्लार्क एवं सोन योजना (The Clark and Sohn Plan)—निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय पुनित-शक्ति का निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापिका का प्रारम्भ—ये सब बातें वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक मौलिक परिवर्तन की माँग करती हैं। व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाने सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावों में एक क्लार्क एवं सोन (Clark and Sohn) का प्रस्ताव है और यह सुझाव या प्रस्ताव बहुत ही विलक्षण और विवेकसम्पन्न है। इस योजना में प्रभावी निःशस्त्रीकरण, विश्व-पुनित-शक्ति की स्थापना और मयुक्त राष्ट्र महासभा की विश्व व्यवस्थापिका में परिणत करना, मयुक्त राष्ट्रमण्डल के सदस्यों को भारत मतदान-अधिकार दिया जाना, सुरक्षा-परिषद् को महामभा के अधीन विश्व कार्यकारिणी के रूप में परिणत करना विश्व पुनित-शक्ति को इस कार्यकारिणी की सत्ता के अधीन कार्य करना, महासभा की सत्ता का

पूर्णरूप से व्यापक होना—आदि बातें सम्मिलित हैं। चूँकि कोई भी राजनीतिक संगठन लम्बे समय तक केवल 'कानून और व्यवस्था' बनाए रखने वाले यन्त्र के रूप में ही काम नहीं कर सकता और यह आवश्यक है कि वह सदस्यों के सामान्य कल्याण के लिए भी कार्य करे, अतः क्लार्क एव सोन योजना में एक विश्व विकास सत्ता (A World Development Authority) की स्थापना की बात शामिल है। यह विश्व-विकास सत्ता अन्तर्राष्ट्रीय जगत के अविक्तित देशों की विकास-योजनाओं में तकनीकी तथा आर्थिक सहायता देगी। विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जो सस्थाएँ या अधिकरण मौजूद हैं वे कायम रहेंगे। सभा (The Assembly) को यह शक्ति सौंपी जाएगी कि वह 'वैधानिक' विवादों ('Legal' Disputes) को, जो शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न करने की सम्भावनाओं से पूर्ण हों, न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) में प्रस्तुत कराए। 'गैर-वैधानिक' विवादों ('Non-legal' Disputes) को, जिनसे विश्व-शान्ति को खतरा हो, एक विश्व-संशोधन-बोर्ड (A World Conciliation Board) के सम्मुख रखा जाएगा। यदि बोर्ड कोई समझौता कराने में असफल रहेगा तो महासभा उस विवाद को विश्व-साम्य-न्यायाधिकरण (A World Equity Tribunal) के पास भेज देगी और साथ ही विशेष बहुमत (A Special Majority) द्वारा यह निर्देश देगी कि न्यायाधिकरण की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। यह निर्णय करने की शक्ति कि कोई विवाद 'वैधानिक' है अथवा 'राजनीतिक', महासभा में निहित होगी।

प्रो. भूनि का कहना है कि क्लार्क एव सोन की योजना में उन व्यावहारिक कदमों को नहीं बताया गया है जो इस प्रकार के सविधानिक ढाँचे की स्थापना के लिए उठाए जाने चाहिए। योजना में विश्व-सरकार की स्थापना की बात कही गई है, लेकिन यह सरकार अधिकांशतः कानून व्यवस्था सम्बन्धी सरकार (A 'Law and Order' Government) होगी। विश्व के सभी भागों में विकास के लिए जो आर्थिक और प्राविधिक प्रबन्ध सोचे गए हैं वे मानव-समाज के सम्मुख उपस्थित महान् कार्यों में सहायता के लिए सर्वथा अपर्याप्त हैं। क्लार्क एव सोन-योजना व्यापक और उत्तम-होते हुए भी इसी प्रकार की अनेक व्यावहारिक कमियों की शिकार है। इस योजना को कार्यरूप देना वर्तमान जटिल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में सम्भव नहीं है, तथापि इससे हमें चिन्तन की दिशाएँ मिलती हैं।

अनिवार्य न्यायिक समझौते के लिए कदम-दर-कदम दृष्टिकोण (The Step-by-Step Approach to Compulsory Judicial Settlement)—न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य न्यायिक क्षेत्र की स्वीकृति के लिए प्रो. लुइस सोन ने कदम-दर-कदम दृष्टिकोण (A Step-by-Step Approach) प्रस्तुत किया है। कदम (The Step) ये हैं—(1) सभी सन्धियों की व्याख्या और प्रयोग के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया जाना, (2) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विशिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्वीकृति, (3) क्षेत्रीय प्रबन्धों के माध्यम से स्वीकृति,

(4) संयुक्त राष्ट्रसंघ को अधिकार देना कि वह सम्बन्धित पक्षों से बाध्यकारी प्रार्थना (A Binding Request) करे कि वे अपने विवाद को न्यायिक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रो मूर्ति का कहना है कि लुइस सोन द्वारा सुभाए गए ये कदम उठाए जाने तभी सम्भव है जबकि अन्यत्र भी अनुकूल विकास हों ताकि विश्व-समुदाय के सदस्यों को यह विश्वास हो जाए कि ऐसे कदमों को स्वीकार करना निश्चित रूप से लाभकारी है।

एक प्रथम चरण (A First Step)—प्रो मूर्ति ने 'एक प्रथम चरण' (A First Step) सुझाया है। उनका कहना है कि यद्यपि हमारा उद्देश्य तृतीय-पक्षीय समझौते के क्षेत्र-विस्तार का होना चाहिए, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि हम ऐसा समझौता केवल न्यायिक न्यायाधिरणों के माध्यम से ही प्राप्त करने का प्रयत्न करें। विधायी अथवा अद्वैत-विधायी अगो की स्थापना की जा सकती है जिन्हें अपनी मध्यस्थता और समझौता कराने की भूमिका निभाने के साथ ही सामूहिक निर्णय देने की क्षमता सौंपी जाए। इन अगो को प्रभावकारी बनाने के लिए उन्हें व्यापक साधनों से सम्पन्न बनाया जाना चाहिए।

हमारा समकालीन विश्व इतना विशाल है और आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विभिन्नताओं और जटिलताओं से इतना परिपूर्ण है कि इसे किसी एक अत्यधिक केन्द्रीकृत सरकारी व्यवस्था (A Highly Centralized Government System) में परिवर्तित करना दुष्कर है। कम से कम आज तो हर मूलतः यह दुष्कर है ही, लेकिन भविष्य में भी लम्बे समय तक कोई सम्भावना नजर नहीं आती। व्यावहारिक तो यही लगता है कि हम उन्हीं वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों को ही अधिक शक्ति-सम्पन्न बनाएँ। उन्हें अधिक साधन-सम्पन्न बनाया जाए और अधिक निर्णायक शक्ति प्रदान की जाए। उनकी गतिविधियों में समन्वय और निर्देशन के जो साधन मौजूद हैं उन्हें सुधारा जाए। यह आवश्यक नहीं है कि सभी विवादों को किसी एक केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत ही सुलझाया जाए। यह हो सकता कि उन्हें विभिन्न उपव्यवस्थाओं को सौंप दिया जाए। प्रत्येक विवाद ऐसी उपव्यवस्था को ही सौंपा जाए जो उसे सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त हो, लेकिन अवश्य ही सभी समझौते समझाने-बुझाने और बाध्यकारी दबाव के सन्तुलित प्रयोग (A Balanced Application of Persuasion and Coercion) पर आधारित हो अर्थात् 'Persuasion' और 'Coercion' दोनों माधनों पर निर्भर किया जाए, अकेले किसी एक साधन पर नहीं।

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ : अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं विश्व सरकार

[(Limitations of National Power : International
Law and World Government)]

“अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन प्रचलित एवं परम्परावादी नियमों का नाम है जिनको सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी व्यवहार में वैधानिक रूप से बाध्य माना जाता है।” —प्रोपेनहीम

राष्ट्रीय शक्ति की तीन प्रमुख सीमाएँ—शक्ति-सन्तुलन, सामूहिक सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान—का विवेचन पूर्ववर्ती अध्याय में करने के उपरान्त अब हम देखेंगे कि इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय कानून और विश्व सरकार की सीमाओं की क्या भूमिका है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रीय शक्ति तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के नियामक और नियन्त्रक के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्त्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रभावशाली रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास हो रहा है उसे देखते हुए विद्वानों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निकट भविष्य में यह यदि निर्णायक तत्त्व के रूप में भूमिका भूदा करे तो आश्चर्य की बात नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ (Meaning of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून को विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। प्रो. प्रोपेनहीम ने लिखा है कि “अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन परम्परागत और आपसी समझौतों से निमित्त अभिसमयात्मक नियमों का संग्रह है जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहार में पालन करने योग्य समझते हैं।” ब्रिटिश कानूनवेत्ता हॉल के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानून आचरण के वे नियम हैं जिनको वर्तमान सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहार में उसे शक्ति के बल पर अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य समझते हैं तथा जिसके अनुसार विवेकशील तथा कर्तव्यपरामर्श व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। वे यह भी समझते हैं कि यदि इनका उल्लंघन किया गया

तो उपयुक्त साधनों द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है।" हंस केल्सन ने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को नियमों का ऐसा समूह माना है जो साधारण परिभाषा के अनुसार राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियमित करते हैं।

सन् 1948 में डॉ पी सी जेसप ने लिखा था कि "अन्तर्राष्ट्रीय कानून सामान्यतः राज्यों के सम्बन्धों पर लागू होने वाले कानून के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक परम्परागत विचार है और कुछ समय से इस विचार का निरन्तर विरोध किया जा रहा है।" वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन आते जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध आजकल राज्यों के पारस्परिक व्यवहार से नहीं रह गया है वरन् इसके अन्तर्गत राज्यों तथा व्यक्तियों के सम्बन्ध और व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध भी शामिल किए जाने लगे हैं। इसी दृष्टिकोण से डॉ जेसप ने राष्ट्रों के आधुनिक कानून की रूपरेखा प्रस्तुत की है। डॉ जेसप का दृष्टिकोण समय की बदलती हुई परिस्थितियों का परिणाम है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिन नियमों का पालन आज सम्पन्न जगत् में हो रहा है। उनके लिखित रूप का विकास मुख्यतः यूरोप और अमेरिका में हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय कानून देश, जाति, वर्ण, धर्म आदि की अपेक्षा नहीं करता, उसकी दृष्टि में सभी राज्य समान हैं। अतः संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर सर्वांगीण और पूर्ण न होने पर भी आज वास्तविक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून बन गया है। इस चार्टर की अवहेलना करने वाले राष्ट्रों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के आर्थिक एवं सैनिक दण्डों की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर को समस्त सदस्य-देशों ने स्वीकार किया है और वे उसे मानने के लिए बाध्य हैं। अतः किसी देश के विधान-मण्डल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर को मान्य कराने का प्रयत्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की विभिन्न परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शब्दों की भिन्नता के बावजूद अर्थ की दृष्टि से इनमें विशेष अन्तर नहीं है। सम्प्रभु राज्यों की सहमति अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का मुख्य आधार है। इनकी स्वयं की शक्ति बाध्यकारी नहीं होती, अतः इसकी सार्यकता सम्बन्धित राज्यों के समर्थन पर निर्भर करती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने की शक्ति राष्ट्रीय कानून की भाँति पुलिस, सेना और दण्ड नहीं है वरन् विश्व-जनमत, अशान्ति का भय आदि हैं। प्रत्येक देश इन्हीं और इसी प्रकार के अन्य कारणों से प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने से बचने की चेष्टा करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर जो विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं उनमें इसके अर्थ से सम्बन्धित निम्नलिखित बातें प्रकट होती हैं—

1. ये राज्यों के पारस्परिक व्यवहार का नियमन करते हैं।
2. ये सिद्धान्तों अथवा नियमों के समूह हैं।
3. ये राज्यों के सामान्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं।

4. इनका स्रोत परम्पराएँ, प्रथाएँ, न्यायालय के निर्णय, न्यायाधीशों का मत राज्यों के कानून, न्याय के सामान्य सिद्धान्त एवं सम्मति के आधारभूत गुण, आदि हैं।

5. इनका पालन सद्भावना एवं कर्तव्यपालन के दायित्व के कारण किया जाता है। ये सम्य राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबन्ध हैं।

6 इनका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की परिभाषा करना, इन अधिकारों की रक्षा का उपाय बताना, अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की व्यवस्था करना, सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों एवं झगड़ों को निवटाना, राज्यों के बीच सद्भाव एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना, आदि हैं।

7 सामान्यतः यह समझा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियमों के संग्रह हैं जिनका उद्देश्य सम्य राष्ट्रों के पारस्परिक आचरण को निमन्त्रित करना है। इन राष्ट्रों का सम्य होना परम आवश्यक है। असम्य राष्ट्र और हिंसात्मक नीति में विश्वास रखने वाले राष्ट्र अपने आपको किसी भी नियम अथवा परम्परा से नहीं बाँधना चाहते, किन्तु सम्य और शान्तिप्रिय देश अपनी जागरूक आत्महित की दृष्टि से नियमों को महत्त्व देने हैं।

क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक वास्तविकता है ?

(Is International Law a Reality?)

यह विचित्र विरोधाभास है कि अनेक विचारक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व में ही सन्देह प्रकट करते हैं। जॉन ओस्टिन, न्यायाधीश कॉलरिज, हॉर्नैण्ड आदि ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून-विरोधी विचार व्यक्त किए हैं। जॉन ओस्टिन ने 'कानून' शब्द का प्रयोग केवल ऐसे नियमों के लिए ही करता उचित समझा है जिनको विधि-निर्माण का अधिकार रखने वाली किसी निश्चित सत्ता द्वारा बनाया गया हो तथा जिसे बल-प्रयोग द्वारा लागू किया जा सकता हो। बल-प्रयोग की शक्ति कानून के पीछे रहने वाला दबाव (Sanction) है। यदि इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर विचार किया जाए तो वह कानून नहीं कहा जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे केवल नैतिक शक्ति होती है। न्यायाधीश कॉलरिज के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक अयथार्थ शब्द है। यथार्थ मान लेने पर अनेक भ्रम उत्पन्न होते हैं। कानून हम उसी को कह सकते हैं जिसे कोई बनाता है, लागू करता है और उल्लंघन करने वाले को दण्ड मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन शर्तों का अभाव है। इसका कारण यह है कि सम्प्रभु राज्य किसी भी आज्ञा अथवा निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्रियों राष्ट्रीय न्यायालयों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाती। ये केवल पारस्परिक समझौते हैं और इनका औचित्य राष्ट्रीय कानून के आधार पर निर्धारित किया जाता है।"

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की वास्तविकता का निषेध करने वाले ने अपने पक्ष में मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं—

1. अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती और इसलिए उसका अनुशीलन केवल सदस्यों की सद्बुद्धि पर निर्भर रह

जाता है। कानून बनाने वाली सत्ता हमेशा उच्चतम होती है और भौतिक शक्ति के बल पर वह दूसरे लोगों को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में इस सबका अभाव है। केवल नैतिक शक्ति ही उन्हें लागू कर सकती है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयाँ सम्प्रभु राष्ट्र होते हैं और इन पर किसी प्रकार का बाहरी नियन्त्रण नहीं रह सकता। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने पर सम्प्रभु राज्य कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे।

3. अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार इनके उल्लंघन का निर्णय सही रूप में नहीं हो पाता।

4. अन्तर्राष्ट्रीय कानून न्यायपालिका की शक्ति के अभाव में भली प्रकार क्रियान्वित नहीं हो पाते और इसलिए वे केवल अव्यावहारिक आदर्श मात्र ही बनकर रह जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व से इन्कार करना वस्तुतः भ्रामक है। यद्यपि यह राष्ट्रीय कानून की सभी विशेषताओं से युक्त नहीं है, तथापि निःसन्देह इसे कानून माना जाएगा क्योंकि कानून के अस्तित्व की आवश्यक शर्तों को यह पूरा करता है—

1. कानून की पहली शर्त समुदाय का अस्तित्व है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस शर्त को पूरा करता है। अन्तर्राष्ट्रीय समाज का अस्तित्व है।

2. दूसरी शर्त आचरण के कुछ नियमों का अस्तित्व है। यह शर्त भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निःसन्देह रूप से पूरी हो जाती है। राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन करने के लिए सैकड़ों वर्षों से नियमों का विकास हो रहा है। ये नियम बहुत कुछ परम्परागत हैं। इन परम्परागत और अलिखित नियमों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा प्रतिदिन अधिक से अधिक नियमों का विकास किया जा रहा है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व की तीसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। राज्यों की सरकारें और सम्पूर्ण सम्य मानवता का लोकमत यह स्वीकार करता है कि यदि आवश्यकता हो तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून बाहरी शक्ति द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए कोई केन्द्रीय सत्ता न हो तो राज्य कानूनों को अपने हाथों में ले सकते हैं। दूसरे राज्यों का हस्तक्षेप और प्रभावित राज्य के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति किसी भी राज्य को कानून भंग करने में रोकती है। समुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर दायित्वों का निर्वाह न करने वाले देशों के प्रति लगाए गए प्रतिबन्धों का उल्लेख करता है।

4. व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को निरन्तर कानून के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों की सरकारें यह मानने लगी हैं कि उनको कानूनी और नैतिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। यद्यपि विश्व-जनमत कानूनों को लागू करने की शक्ति नहीं रखता, किन्तु वह यह मानता है कि ये कानून लागू किए जाने चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन प्रायः युद्ध के समय

बहुत होता है, किन्तु उत्संघन करने वाले देश यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उनका व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुस्यू है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन जिन दबावों के कारण किया जाता है उनमें मुख्य रूप से उत्संघनीय राज्य की इच्छा है। अपने कार्यों की सफलता और असफलता के लिए एक राज्य स्वयं ही उत्तरदायी होता है। युद्ध का भय तथा शक्तिपूर्ति की भावना प्रायः सभी सम्य देशों को भयभीत रखती है। विश्व लोकमत का प्रभाव प्रत्यक्ष इन्हीं तत्त्वों का संयोग राज्यों, सम्प्रभुओं, संसदों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा या तो स्वयं को सामान्यतः स्वीकृत नियमों से बाँधा हुआ अनुभव करता है अथवा यदि ये इनका उत्संघन करते हैं तो उनको सम्बन्धित कारणों का स्पष्टीकरण करना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के लागू होने के पीछे दबाव चाहे कुछ भी हो, किन्तु यह सब है कि जब विश्व के देश इनका स्वयं के तथा विश्व समाज के हित में अनुशीलन करते हैं तो इनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को इतनी तीव्रता के साथ अनुभव किया जाता है कि राष्ट्रीय कानून इनके सुगम संचालन के लिए उपयुक्त तन्त्र की स्थापना करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अधिकांश भाग राष्ट्रों के दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में नियमित रूप से स्वीकार किया जाता है तथा इनका उत्संघन कदाचित् ही किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार

(The Basis of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का आधार यह सरल तथ्य है कि राज्य परस्पर निर्भर हैं। अपने औपचारिक सम्बन्धों में राज्यों को ऐसे व्यक्ति माना जा सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रशासित होते हैं। जो शक्तियाँ शक्ति को नागरिक समाज में एकीकृत करने के लिए प्रेरित करती हैं और अलग राष्ट्रीय समूहों से सङ्गठित करने के लिए उत्साहित करती हैं वे ही विभिन्न राज्यों को उनके पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन करने के लिए कानून की स्थापना हेतु प्रेरित करती हैं। राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना अपने लिए क्यों आवश्यक मानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर उन विभिन्न आधारों को प्रकट करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुशीलन के लिए अनिवार्य हैं।

1. पहला सिद्धान्त मौलिक अधिकारों का सिद्धान्त (Theory of Fundamental Right) है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की भाँति राज्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं—जैसे स्वतन्त्रता, समानता आत्मरक्षण, पारस्परिक सम्मान और एक-दूसरे के साथ व्यवहार आदि। इस मत के विरोध में कई बातें कही जाती हैं। उदाहरण के लिए यह मानता गलत है कि राज्यों को कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हुए रहते हैं और ये उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त नहीं होते। कोई भी अधिकार उस समय तक महत्त्वहीन होता है जब तक उसे उचित मिट्ट करने वाली प्रक्रिया न हो।

दूसरा विरोध यह है कि इसमें राज्यों के सामूहिक सम्बन्धों की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप को प्रधानता दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्यों के व्यक्तिवादी अधिकारों पर जोर देना अधिक महत्व नहीं रखता। इसके स्थान पर उन्हें एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ज्ञान होना चाहिए।

2 अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार का दूसरा सिद्धान्त सहमति का सिद्धान्त (Consent Theory) है। विभिन्न देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि इन देशों ने अपनी सहमति से इसे स्वीकार किया है। जब आचरण के किसी नियम को बाध्यकारी रूप से लागू होने वाला समझ लिया जाता है तो वह कानून बन जाता है। औपचारिक सन्धियाँ और अभिसमय सम्बन्धित पक्षों की स्वीकृति पर आधारित होते हैं। इस प्रकार की प्रत्यक्ष स्वीकृति के साथ में विशेष निद्धान्तों के सम्बन्ध में राज्यों की अप्रत्यक्ष स्वीकृति भी रहती है। यद्यपि सभी राज्य सम्प्रभु हैं, किन्तु सम्प्रभु राज्य अपनी प्रभुता का प्रयोग करते हुए आचरणों के कुछ नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ये आचरण के नियम अन्तर्राष्ट्रीय कानून की रचना करते हैं।

विभिन्न राज्य अपनी इच्छा से सम्प्रभुता को सीमित कर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। अनेक विद्वानों का तर्क है कि राज्यों की सहमति पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धान्त उन मान्यताओं को स्पष्ट करने में असमर्थ है जिन पर विभिन्न सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रारम्भ में निर्भर थीं। पुनश्च, कानूनों का पालन सहमति की अपेक्षा बाध्यता के कारण किया जाता है। हम केल्सन के कथनानुसार, "जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के प्रतिकूल राज्य के कानूनों को मानने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं होता, उसी प्रकार कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बन्धन को अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करता।"

3. एक अन्य आधार वर्तमान परिस्थितियों में उत्पन्न राज्यों की यह भावना है कि इन कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। यदि कानून केवल विषयपरक रहा होता तो सम्बन्धित पक्षों के हितों के अनुसार इसमें आए दिन परिवर्तनों की माँग होनी रहती और कानून जैसी पवित्रता न रह पाती। विचारकों का मत है कि वर्तमान परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून से भिन्न कोई आधार तलाश करना केवल असाध्य ही नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से हानिकारक भी है। आधुनिक परिस्थितियों में विभिन्न राज्य सामाजिक प्राणी बन गए हैं और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समाज के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर रहना है। विभिन्न राज्यों की एक-दूसरे पर निर्भरता आज के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का तथ्य बन गई है और एक राज्य का हित दूसरे राज्य के हित के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों का नियमन करने के लिए कानून की जो आवश्यकता है वही राज्यों के आपसी सम्बन्धों का नियमन करने के लिए है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व सम्भवतः इसलिए है क्योंकि यह अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता है। राज्यों की पारस्परिक निर्भरता ने जाने-अनजाने

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास को प्रेरणा दी है। ये कानून विभिन्न राज्यों के कानूनी सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह एक पुराना कार्य है जिसे यह आज की उलझी हुई दुनिया में भी सम्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त वारसाधिकार के मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून अनुशासित आचरण प्रेरित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सदस्य-राज्यों को कानून की दृष्टि से समान समझा गया है। यह सच है कि शक्ति, प्रदेश और ऐसी ही अन्य बातों के सम्बन्ध में राज्य समान नहीं हैं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सदस्य के रूप में सिद्धान्ततः वे समान हैं। उनकी यह समानता सम्प्रभुता के सिद्धान्त पर आधारित है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रणालियाँ (Methods of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विश्लेषण की प्रणालियों में तीन उत्प्रेक्षणीय हैं—

1. शक्ति-प्रणाली—शक्ति-प्रणाली का समर्थन मॉर्गेंथो जैसे लेखकों द्वारा किया गया है। मॉर्गेंथो के अनुसार समस्त राजनीति की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए युद्ध की स्थिति है। व्यक्ति की भाँति राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्रों के मस्तिष्क एवं कादों पर नियन्त्रण करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीतिक शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह शक्ति-सम्पन्न लोगों को उनसे सम्बन्धित करती है जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये सम्बन्ध धमकियाँ, प्रभावों आदि के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। शक्ति के लिए संघर्ष (आन्तरिक और बाह्य) अपरिहार्य है। युद्ध में शत्रुओं के सहार जैसी भावनाएँ दूसरों पर शासन करने की इच्छा से प्रेरित होती हैं। शक्ति-राजनीति (Power Politics) के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक विशेष समूह या हित को राष्ट्रीय शक्ति पर निर्भर करता है।

शक्ति-प्रणाली की समझने के कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, यह हमें उन शक्तियों के सम्बन्ध में यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त का रूप निर्धारण करती हैं। दूसरे, यदि शक्ति को उचित रूप से समन्वित किया जाए और स्वस्थ मार्गों की ओर प्रेरित किया जाए तो यह राज्यों के आपसी सम्बन्धों में शान्ति ला सकेगी। तीसरे, लॉसेल तथा कंपलान का कहना है कि शक्ति प्रणाली हमें अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के महत्त्व से परिचित कराती है तथा इनकी नीति का आधार बनाने के लिए प्रेरित करती है।

पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विश्लेषण की यह प्रणाली दोषपूर्ण भी है। यदि इस प्रणाली को अपना लिया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून शक्ति का कानून बन जाता है। वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून में कानून की शक्ति (Power of Law) होनी चाहिए। 'शक्ति' द्वारा कानून की रचना न होकर वह कानून पर निर्भर हो। दूसरे, यदि इस प्रणाली को मान लिया जाए तो विदेश-नीतियाँ इसी विकृत तथ्य पर निर्भर हो जाएँगी और विश्व-शान्ति खतरे में पड़ जाएगी। तीसरे, शक्ति-प्रणाली द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून की नींव को कमजोर किया जाता है।

2. न्यायिक-प्रणाली—अन्तर्राष्ट्रीय कानून की न्यायिक प्रणाली का समर्थन केल्सन आदि विद्वानों ने किया है। केल्सन के मतानुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन के लिए राजनीतिक प्रणाली का प्रयोग खतरनाक है। यह दृष्टिकोण केवल उसी अध्ययनकर्त्ता के लिए उपयुक्त माना जा सकता है जो अपने देश के अनुकूल शक्ति-राजनीति को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सही सिद्ध करना चाहता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून की छाया में राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन है। इसके लिए न्यायिक प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायवेत्ता का कार्य यह है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समाज के नियमों के क्षेत्र को विस्तृत कर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र को व्यापक बनाए।”

न्यायिक प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून के रचनात्मक और प्रतिबन्धात्मक पहलुओं पर बल देती है। यह दृष्टिकोण हमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र की अग्रगण्यता से परिचित करता है। यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं को दूर करने का निर्देश नहीं दिया जाता। यह न्यायाधीशों का दृष्टिकोण अपनाकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून की विषयपरक प्रकृति पर प्रकाश डालता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल कानून नहीं है, एक सामाजिक दर्शन भी है जिसके प्रति सजगता के बिना अन्तर्राष्ट्रीय कानून की रचना का कार्य अव्यावहारिक हो जाएगा।

3. समाजशास्त्रीय प्रणाली—अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विश्लेषण की समाजशास्त्रीय प्रणाली सबसे अधिक स्वीकृत है। ‘कानून-समाजशास्त्र’ एक नया विषय है जिसके अन्तर्गत कानून की सम्पूर्ण सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। कार्ल मेनहीम ने सामाजिक विज्ञानों के लिए एक नई प्रणाली का उल्लेख किया है। उसने ज्ञान के निपेधात्मक परम्परागत तरीकों को चुनौती दी है जिनमें विषयपरक या व्यक्ति अथवा सामूहिक आधारों को छोड़कर केवल वस्तुनिष्ठता पर विचार किया जाता है। मेनहीम का कथन है कि वस्तुनिष्ठता विषय से सम्बन्ध रखती है और विषय हमको ज्ञान के सकारात्मक, रचनात्मक और मूल्यात्मक पहलुओं को समझने में मदद करता है।

आजकल समाजशास्त्रीय प्रणाली के साथ-साथ अनुभववादी प्रणाली भी अपनाई जाती है। यह प्रणाली परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक प्रणाली द्वारा सामाजिक वास्तविकताओं का निर्धारण करती है। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय कानून सामाजिक विज्ञान बनता जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत

(Sources of International Law)

प्रो. स्टार्क ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों को निम्नलिखित चार वर्गों में बांटा है—

1. रीति-रिवाज (Customs)
2. सन्धियाँ (Treaties)

3. पंच-निर्णय अथवा न्यायालयों के निर्णय (Decisions of Arbitral or Judicial Tribunals)

4. विधिशास्त्रियों के ग्रन्थ (Juristic Works)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर द्वारा स्थापित) की सविधि (Statute) के अनुच्छेद 38 'ए' में उल्लेख किया गया है। तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निम्नलिखित चार स्रोत हैं—

1 सामान्य या विशेष अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Conventions) जिन्हें ऐसे नियमों की स्थापना होती हो जिन्हें प्रतिस्पर्द्धी राज्यों ने प्रकट रूप से स्वीकार कर लिया हो।

2. अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाज (International Customs) जो इस बात का प्रमाण है कि किन्हीं सामान्य व्यवहार (Practice) को कानूनी मान्यता मिल गई है।

3. कानून के ऐसे सामान्य सिद्धान्त (General Principles of Law) जिन्हें सम्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया है।

4. अनुच्छेद 59 के उपबन्धों के अधीन न्यायिक निर्णय (Judicial Decisions) और विभिन्न राष्ट्रों के उत्कृष्ट योग्यता वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधि-विशेषज्ञों के कथन, विधि के नियमों के निर्धारण के लिए सहायक साधनों के रूप में।

उपर्युक्त प्रमुख स्रोतों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोत इस प्रकार हैं—अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (International Comity), सन्धियों के अतिरिक्त राजकीय पत्र (State Papers), राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिए जारी किए गए निर्देश, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रस्ताव, विभिन्न देशों की पार्लियामेंटों के तथा विधान सभाओं के कानून, न्यायालयों के निर्णय, अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं की तथा इस विषय पर ग्रन्थ लेखकों की सम्मतियाँ।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकेन्द्रित स्वरूप

(Decentralized Nature of International Law)

वैधानिक समुदाय के सदस्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, अतः यह विकेन्द्रित व्यवस्था कहलाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के निर्माण के तरीके, उनकी व्याख्या के रूपों और व्यवहार की प्रणालियों आदि से यही पुष्टि होती है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप विकेन्द्रित है, राष्ट्रीय कानून की भाँति केन्द्रित नहीं। माँगेंवो के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय कानून की विकेन्द्रित प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय समाज के विकेन्द्रित ढाँचे का आवश्यक परिणाम है। जिस प्रकार एक राष्ट्र के कानूनों का निर्माण एवं संचालन कुछ सुव्यवस्थित एवं सुविकसित अंगों द्वारा किया जाता है वैसे कोई व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचलित नहीं है और न ही हो सकती है। जब तक अपने-अपने क्षेत्रों में सम्प्रभु राज्यों द्वारा विश्व-समुदाय की इकाइयों की भूमिका अदा की जाती है तब तक कानून का निर्माण करने वाली तथा

उसे लागू करने वाली कोई केन्द्रीय व्यवस्था जन्म नहीं ले सकती। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अस्तित्व एवं व्यवहार दो तत्वों के कारण है—

- (i) राज्यों के समान अथवा एक-दूसरे के पूरक हित,
- (ii) राज्यों के बीच सन्तुलन की स्थापना।

यह कहा जाता है कि जहाँ समुदायों के हित नहीं होते तथा उनके बीच शक्ति का सन्तुलन नहीं पाया जाता, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं रह सकता। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास एवं पालन वस्तुपरक सामाजिक शक्तियों (Objective Social Force) का परिणाम है। प्रोफेसर ओपेनहीम ने शक्ति-सन्तुलन को अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अभिन्न शर्त माना है। उनका मत है कि यदि शक्तियाँ एक-दूसरे का नियमन नहीं कर सकती तो कानून का कोई प्रभाव नहीं रह सकता क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र स्वभावतः मनमानी करना चाहेगा तथा वह कानून का उल्लंघन करेगा। सम्प्रभु राज्यों के ऊपर कोई केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता नहीं रह सकती, इसलिए यह आवश्यक है कि शक्ति-सन्तुलन द्वारा राष्ट्रों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वेच्छाचारी होने से रोका जाए। समरूप एवं परस्पर सहायक हित (Identical and Complementary Interests) भी विकेन्द्रीकरण रूप में सदैव क्रियाशील रहते हैं। वे प्रत्येक वैधानिक व्यवस्था के विधायी, न्यायिक एवं कार्यपालक तीनों ही कार्यों पर प्रभाव डालते हैं। मॉर्गेंथो ने इन्हे जीवन-रक्त की सजा दी है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण (Creation of International Laws)

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण नहीं होता इनका प्रायः विकास किया जाता है। सम्प्रभु राष्ट्रों के ऊपर ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे सर्वोच्च कहा जा सके और जो ऐसे कानूनों का निर्माण कर सके जिनको राष्ट्रों द्वारा बाध्यकारी रूप में मनवाया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास दो रूपों में होता है अथवा यो कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण दो प्रकार से होता है—प्रथम प्रकार से तो इन कानूनों के 'व्यवहार एवं प्रचलन की क्रमिक प्रक्रिया' द्वारा विकास होता है। दूसरे प्रकार के अनुसार ये 'सन्धियों की रचना एवं स्वीकृति' के माध्यम में जन्म लेते हैं। प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास मुख्यतः प्रचलन एवं व्यवहार द्वारा किया गया है, किन्तु इन कानूनों की व्याख्या करने वाला कोई अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय न होने के कारण इनका व्यवस्थित रूप से विकास नहीं हो पाता। यह निश्चय करना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन-सी प्रथा या प्रचलन कानून बन जाएगा। अनेक बार ऐसा होता है कि रीति-रिवाज प्रचलित होने पर भी सार्वभौमिक (Universal) नहीं बन पाते। प्रचलित कानूनों (Customary Law) की बड़ी कमी यह भी है कि इनके द्वारा विश्व की घटनाओं के परिवर्तित एवं गत्यात्मक (Dynamic) रूप के साथ समायोजन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा सन्धि अथवा सम्मेलनों में नवीन नियमों का निर्माण किया जाता है, सन्धियाँ प्रायः प्रचलित कानून के आधार पर की जाती हैं, सन्धि की इच्छावादी राज्य

होते हैं। सन्धियों की कार्यवाही राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है तथा इसके उपबन्धों का प्रभाव केवल उन देशों पर पड़ता है जो इसमें भाग लेते हैं। सन्धि एवं समझौते द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है। वे मुख्यतः राज्यों की सामान्य समस्याओं का मुकाबला करने के सहयोगपूर्ण प्रयास का प्रतीक होते हैं। कुछ का सम्बन्ध सामाजिक, व्यावसायिक एवं आर्थिक मामलों से होता है जबकि दूसरे शान्ति और युद्ध जैसी समस्याओं से सम्बन्धित रहते हैं। राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के परिपत्रों द्वारा सन्धियों के मार्ग को आसान बना दिया गया था, ताकि कूटनीति को दूर किया जा सके। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सन्धि को पहले पंजीबद्ध (Registered) कराया जाएगा तथा बाद में सचिवालय उसे प्रकाशित कर देगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रकार

(The Kinds of International Laws)

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण कई प्रकार से होता है और इसके स्रोत भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन कानूनों की प्रकृति, रूप एवं लक्ष्य में विभिन्नता आ जाए। कई आपारों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विभाजन किया जाता है। इनमें प्रमुख विभाजन अप्रलिखित हैं—

- (1) व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Private and Public International Law)
- (2) प्रक्रिया सम्बन्धी एवं वास्तविक कानून (Procedural and Substantial Law)
- (3) शान्ति, युद्ध एवं निरपेक्षता के नियम (Laws of Peace, War and Neutrality)
- (4) विशेष और सामान्य या सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Particular and General or Universal Law)
- (5) शक्ति, सहयोग और परस्पर सम्बन्धों के कानून (Law of Power, Co-ordination and Reciprocity)।

प्रो डिकिन्सन (Professor Edwin D Dickinson) ने बताया है कि व्यक्तिगत अधिकारों एवं कर्तव्यों से सम्बन्धित विषयों पर न्यायीकरण एवं नियमन (Adjudication and Regulation) की समस्या उठ खड़ी होती है क्योंकि वस्तुओं एवं व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश में आवागमन होना ही रहता है तथा राष्ट्रीय सीमाओं के परे सम्पत्ति, परिवार, समझौते, आदि भी होते ही हैं। पामर तथा पकिंस ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो अन्य रूपों का भी वर्णन किया है। एक तो समुद्री व्यापार का कानून है जिसे वे एडमिरैल्टी कानून (Admiralty Law) कहते हैं और इसके दूसरे प्रकार को अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (International Comity) का नाम देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में युद्ध-कानून और शान्ति-कानून का नाम भी उल्लेखनीय है।

युद्धकानूनों की आवश्यकता इस कारण हुई कि जहाँ न्याय की स्थापना एवं शोषण व अन्धपाय का विरोध करने में शान्तिपूर्ण साधन सफल नहीं हो पाते, वहाँ युद्ध अपरिहार्य बन जाता है। यह एक देश की आत्म-रक्षा का अन्तिम तरीका है। कई स्थितियों में युद्ध न्यायपूर्ण एवं धर्मयुद्ध बन जाते हैं, किन्तु धर्मयुद्धों में भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अनेक अभिसमयों एवं अभिलेखों द्वारा भूमि और समुद्र पर युद्ध के विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया है। ये कानून युद्ध के घायलों की देखभाल, युद्ध-बन्धियों के साथ बर्ताव, मेडीकल कर्मचारियों को सुविधाएँ देना, निषिद्ध हथियार एवं अभिकरण, शत्रु की जीती हुई भूमि में सैनिक कमाण्डर की शक्ति, निष्पक्ष राष्ट्रीय के कर्त्तव्य एवं अधिकार, जहरीली गैसों का प्रयोग आदि बातों से सम्बन्धित है। यह माना जाता है कि युद्ध-कानूनों ने युद्ध को मानवीय बनाने में भारी सहायता की है। प्रायः सभी देशों द्वारा इनका अनुपालन किया जाता है, किन्तु अभी तक वायु युद्ध के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रभावशाली कानूनों का निर्माण नहीं किया गया। प्रथम विश्व-युद्ध के कानून प्रायः निष्पक्षतापूर्ण कानून थे। इन कानूनों का पालन युद्ध के समय न किया जा सका। जहाँ इन कानूनों का व्यवहार सम्भव था वहाँ भी इनकी अवहेलना की गई है। आज जबकि समग्र युद्धों (Total Wars) का प्रचलन है, निष्पक्षता लगभग असम्भव है। फिलिप जैसप (Philip C Jessup) के विचार से यदि समाज के वर्तमान या भविष्य की एकता को देखा जाए तो विशिष्ट होगा कि निरपेक्षता (Neutrality) आज एक समाज-विरोधी स्थिति (Anti-social Status) बन गई है।

शान्ति-कानून भी युद्ध-कानूनों की भाँति विश्व व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किन्तु शान्ति-कानूनों का विषय-क्षेत्र युद्ध-कानूनों से पर्याप्त भिन्न रहता है। शान्ति-कानूनों के विषय-क्षेत्र को डिकिंसन (Professor D kinson) द्वारा मुख्यतः छ. भागों में विभक्त किया गया है जो निम्न प्रकार हैं—

1. राष्ट्रीय राज्यों के जन्म, स्वीकृति, जीवन और मृत्यु से सम्बन्धित;
2. राष्ट्रीयता एवं उसके तत्वों से सम्बन्धित;
3. राष्ट्रीय प्रशासन से सम्बन्धित,
- 4-5. सम्झौतों, सम्पर्कों और अधिकार-क्षेत्रों से सम्बन्धित;
6. विवादों के निपटारे से सम्बन्धित कानून।

पामर तथा पर्किंस (Palmer and Perkins) के अनुसार इनमें से प्रत्येक पहलू पर प्रचुर साहित्य उपलब्ध है तथा इन पहलुओं के माध्यम से ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को विभाजित करने वाला प्रत्येक आधार पुनरोक्ति, अधूरेपन एवं परस्पर विरोध जैसे अवगुणों से दूषित है। ये दोष स्वाभाविक हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति की उपज हैं। मॉर्गेंथौ का कथन है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने में क्या क्या व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य करने होते हैं तथा उमरी व्याख्या के लिए कौन से न्यायिक (Judicial) और उन्हें लागू करने के लिए कौन-कौन से कार्यपालिका (Executive) सम्बन्धी कार्यों की

साधना की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यों का सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, किन्तु इसके न्यायिक तथा कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों का सुधार करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इन सब प्रयासों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकेन्द्रित स्वरूप (Decentralized Nature) सबल बना है और आज विकेन्द्रित स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सार (Essence) बन गया है। जो सिद्धान्त विकेन्द्रीकरण को अपरिहार्य बना देते हैं वे सम्प्रभुता के सिद्धान्त में प्राप्त होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे दबाव (Sanctions Behind International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता। इसका पालन स्वतन्त्र एवं सम्प्रभु-राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर है जो सदैव स्वार्थ में लिप्त तथा शक्ति-वृद्धि के लिए सतन्त्र रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय स्वार्थ एवं राष्ट्रीय शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकता है, किन्तु प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप में तो वह एक प्रभावशाली बाधक का ही कार्य करता है। राष्ट्रों द्वारा जानबूझकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की घोषणा की जाती है पर फिर भी ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं जिसके द्वारा उनको इस अधाक्षिणीय कार्य के लिए दण्डित किया जा सके। तथ्यों के आधार पर कुछ विचारकों ने यह मत प्रकट किया है कि ज्यों-ज्यों अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सुधार होता है अर्थात् इसका स्तर ऊँचा उठता है, त्यों-त्यों इसके मानने वालों की, इस पर असर करने वालों की संख्या भी कम होनी चली जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कुछ निश्चित परिस्थितियों का परिणाम होता है। एक राष्ट्र-विशेष के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण भी उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्रियान्वयन में अनेक परिस्थितियों, मनोभावों, घटनाओं, आदि का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए एक राष्ट्र को प्रेरित करने वाले विभिन्न तत्वों में मुख्य तत्व इस प्रकार हैं—

(1) आशय, (2) सुविधा, (3) आत्म-चेतना, (4) अनौपचारिक दबाव, (5) स्वार्थ (Self-Interest), आदि। प्रत्येक राष्ट्र एक समय में अनेक प्रकार के हल अपनाने के लिए स्वतन्त्र रहता है; उदाहरण के लिए, वह दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक या आर्थिक प्रभाव का उपयोग कर सकता है। ये प्रभाव प्रायः सभी वैधानिक व्यवस्थाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके प्रतिरिक्त एक राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को क्रियान्वित कराने के कुछ अन्य औपचारिक साधन भी अपनाए जा सकते हैं। इन साधनों को प्रायः अनुशास्ति या दण्ड (Sanctions) कहा जाता है। श्लीचर (Schleicher) के शब्दों में, अनुशास्ति एक ऐसी क्रिया है जो कि साधारणतः प्रवृत्ति होती है, किन्तु कानून तोड़ने वाले के विरुद्ध बंध-समुदाय (Legal

Community) द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है।¹ कानून का पालन करने वाले के विरुद्ध ये प्रयुक्त नहीं की जाती। राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के व्यवस्था-पत्रों में इस प्रकार की अनुशास्तियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा इस प्रकार के कदम सामूहिक सुरक्षा प्रयत्नों के प्रांशिक रूप में ही अपनाए गए। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि यदि सामूहिक सुरक्षा के शान्तिपूर्ण साधन असफल हो जाएँ तो शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि एक आदर्श कानून को क्रियान्वित करने के साधन भी वैधानिक ही होने चाहिए; शक्ति द्वारा उनको लागू कराने का अर्थ होगा कानून की आत्मा का हनन कर देना। इसी आधार पर श्लीचर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि "संयुक्त-राष्ट्रसंघ यथार्थ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को नष्ट करता है, यह इनको लागू करने का स्वयं उत्तरदायित्व नहीं लेता।"²

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मूल्यांकन (An Evaluation of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने अनेक बार अन्तर्राष्ट्रीय मनमुटावों को पंदा होने एवं बढ़ने से रोका है, फिर भी जैसा कि अधिकांश विचारकों का मत है अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परिणाम आशाजनक एवं अधिक प्रभावशाली नहीं हो सके हैं। पामर तथा पकिंस ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पाँच सीमाओं का वर्णन किया है—

- 1 व्यवस्थापन-कार्य की अपूर्णता,
- 2 न्यायिक कार्यों में विभिन्न गम्भीर सीमाएँ,
- 3 प्रभावशाली प्रयोग (क्रियान्विति) की कमी,
- 4 अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कार्यों एवं क्षेत्रों पर सीमाएँ,
- 5 कानून के उद्देश्य एवं प्रकृति के सम्बन्ध में गलतफहमियाँ।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ये सभी सीमाएँ अन्तर्राष्ट्रीय समाज के वर्तमान चरित्र में निहित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समाज सामान्यतः बंध व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता तथा उसका मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। जैसप (Philip Jessup) का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की मूल कमजोरी यह है कि परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल राज्यों के बीच का कानून है; यह व्यक्तियों के बीच का या व्यक्ति और राज्यों के बीच का कानून नहीं है।³ जैसप का विचार है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक रूप का विकास करना है तो व्यक्तियों-सहित अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विस्तार करना होगा। उन्होंने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था की दो मूल कुञ्जियाँ हैं—प्रथम, राष्ट्रीय कानून की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी सीधे व्यक्ति पर लागू होने चाहिए। वह

1 Schleicher : International Relations, p. 385.

2 Schleicher : Ibid, p. 385.

3 Philip Jessup : A Modern Law of Nations.

परम्परावादी कानून की भाँति व्यक्ति से दूर नहीं रहना चाहिए। दूसरे, उस हित का स्पष्टीकरण होना चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून कि पालन करने से पूरा होनेवाला है। कानूनों का उल्लंघन भी केवल राज्यों की ही समस्या नहीं मानी जानी चाहिए। हैस केल्सन (Hans Kelsen) के मतानुसार, युद्ध को रोकने का एक प्रभावपूर्ण साधन यह है कि युद्ध क्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का उत्तरदायित्व पूरी तरह से सरकार के सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप में डाला जाना चाहिए। किसी राइट ने इस मत के समर्थकों के विचारों की व्याख्या करते हुए बताया है कि ये सिद्धान्त रूप से विश्व-समाज के सम्प्रभु राष्ट्रों द्वारा विश्व-मगठन में परिवर्तन करना चाहते हैं जिसमें कि मयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा की जाएगी, अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों की सजा दी जाएगी तथा व्यक्ति एवं राज्य दोनों पर कानून को लागू किया जाएगा।

विश्व-शान्ति की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून की बहुत प्रशंसा की जाती है, किन्तु कुछ विचारकों के मतानुसार, यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक पहलू मात्र है और किसी भी अर्थ में यह एक महत्त्वपूर्ण पहलू नहीं है। कहा जाता है कि युद्ध और शान्ति पर प्रभाव डालने वाले बड़े-बड़े मसले अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिधि के बाहर रहते हैं। जिन विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हस्तक्षेप है उनमें भी यह आवश्यक नहीं कि प्रभावित राष्ट्र उसका आदर करें। राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न इसके सफल संचालन के मार्ग की बाधा है। इन सबके बावजूद पामर तथा पेंकिस जैसे विचारकों का मत है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था का निर्माण करने में निष्पक्ष प्रयास करता है जिसके अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की शान्ति व स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।¹

अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक प्रकार से उन सभी प्रयासों के परिणामों को पजीबद्ध कर देता है जो शान्ति की खोज में किए जाते हैं। डिकिंसन (Dickinson) के शब्दों में, शान्ति का प्रत्येक दिवस कानून के विस्तार का एक समय है। सीनेटर टाफ्ट ने कहा था कि विश्व-शान्ति तब तक असम्भव है जब तक कि राष्ट्र उनके परस्पर के सम्बन्धों को नियन्त्रित करने वाले किसी निश्चित कानून पर सहमत नहीं हो जाते। राष्ट्रों को सहमत होकर यह मानना चाहिए कि वे अपने झगड़ों को बिना निषेधाधिकार का प्रयोग किए न्यायाधिकरण (Adjudication) के लिए प्रस्तुत करेंगे तथा निष्पक्ष न्यायालय का जो निर्णय होगा उसे अनिवार्य मानेंगे। इसके लिए जैसप अन्तर्राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि जब तक विश्व-सरकार की स्थापना द्वारा सम्पन्न राष्ट्रों की व्यक्तिगत इच्छा को सामूहिक इच्छा के अधीन नहीं बना दिया जाता, तब तक कानून के अन्तिम सक्षय, अर्थात् मानव-संघर्ष के सुलझाने में शक्ति-प्रयोग के निषेध को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।² अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को सफल रूप से संचालित करने के लिए विश्व के

1 Palmer and Perkins : op. cit., p. 327.

2 Jessup : A Modern Law of Nations, p. 2.

अधिकांश देशों में सहयोग की भावना का होना अनिवार्य है। यह भावना न केवल कानून-निर्माण के बाद बल्कि कानून-निर्माण के पहले भी होनी चाहिए। विश्व सरकार की स्थापना तथा निःशस्त्रीकरण के प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं।

विश्व-सरकार (World Government)

राष्ट्रवाद और प्रभुमत्ता पर आधारित तथा शक्ति-राजनीति द्वारा संचालित वर्तमान राज्य-व्यवस्था किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा-व्यवस्था के मार्ग में बाधक है, अतः बहुत से विचारकों का मत है कि हमें सार्वभौम राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था के विकल्प की ढूँढ़ निकालने और उसे प्रतिष्ठित करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने चाहिए। विश्व सरकार का विचार ही एक ऐसा विकल्प समझा गया है जो राष्ट्रीय सम्प्रभुता को विश्व-सत्ता में हस्तान्तरित करने पर सम्भव हो सकता है।

विश्व-सरकार की मान्यता की विशेषताएँ (Characteristics of the Concept of World Govt.)

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के समर्थक विचारकों ने विश्व-सरकार के सम्बन्ध में जो विभिन्न मत प्रकट किए हैं उनसे मान्यता की कनिष्ठ विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं—

1. विश्व-सरकार शान्ति और व्यवस्था की निर्माणक है—यह मान्यता प्रस्तुत की गई है कि विश्व में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए विश्व-सरकार का निर्माण आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति रहेगी ताकि विश्व के देश परस्पर सघर्षरत न हो सकें और सर्वोच्च शक्ति ने अधीन अनुशासन कायम रखें। क्लाइ के शब्दों में, “सामान्य रूप से विश्व-सरकार के मिद्धान्त का आशय ऐसी सत्ताधारी, शक्तिशाली केन्द्रीय संस्थाओं का निर्माण करना है जो राज्यों के बीच सम्बन्धों का, मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने के लक्ष्य के लिए प्रवृत्त कर सके।”¹

2. राष्ट्रीय सम्प्रभुता का विरोधी—वर्तमान विश्व ऐसे राष्ट्रों से मिलकर बना है जो अपने क्षेत्र में सम्प्रभु हैं और जिनका आन्तरिक एवं बाह्य व्यवहार में मनमाने और स्वतन्त्रता का प्रयोग बट्टापी नीति से आगे बढ़कर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की मारी शान्ति नष्ट कर देना है। इस प्रकार की सम्भावनाओं से बचने के लिए विश्व-सरकार की स्थापना एक प्रभावशाली उपाय है। राष्ट्रीय सम्प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीय दावों और समस्याओं द्वारा ही प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता, इसके लिए राज्यों की व्यक्तिगत सम्प्रभुता का एक विश्व-शक्ति को हस्तान्तरण करना होगा। माँगेन्थो के शब्दों में, “आवश्यक है कि सम्प्रभु राष्ट्रों के इस विश्व-समाज को व्यक्तिगत

1 Claude J. L. : Power and International Relations, p. 206.

राष्ट्रों से उच्चतर समुदाय (Supranational Community) में परिवर्तित कर दिया जाए।¹

3 विश्व-सरकार शक्ति-प्रवन्ध के रूप में—राज्यों के शक्ति-मन्वन्धों की व्यवस्था के लिए प्रारम्भ से ही जो विभिन्न विचार समझाए गए हैं, वे प्रायः असफल रहे हैं। कहा जाता है कि विश्व-सरकार की स्थापना इस दिशा में अति प्रभावशाली उपाय सिद्ध होगी। विश्व-सरकार की मान्यता का महत्व इस बात में है कि इसे सर्व-सम्मति से शक्ति-प्रवन्ध की समस्या का एक उपयोगी सैद्धान्तिक सुधार माना गया है। वर्तमान विश्व की अराजकता को विश्व-सरकार की स्थापना के अनिवार्य ग्रन्थ किसी साधन द्वारा दूर नहीं किया जा सकता।

4. सामूहिक सुरक्षा का अग्रगण्य कदम—शक्ति-सन्तुलन और सामूहिक सुरक्षा विश्व-शान्ति के प्रभावकारी उपाय सिद्ध नहीं हुए हैं। विश्व-सरकार इनका अग्रगण्य कदम है। ऐसा दो दृष्टियों से है—प्रथम, यह साहित्यिक इतिहास-क्रम में एक बाढ़ की मान्यता है, एवं द्वितीय, यह शक्ति के केन्द्रीकरण का प्रतीक है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ने शक्ति-सन्तुलन द्वारा स्थापित विवेकीकृत व्यवस्था का सही विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जबकि विश्व-सरकार की मान्यता हम आलोचना से परे है और सामूहिक सुरक्षा की कमियों को दूर करने में प्रभावी निष्ठ हो सकती है।

5 विश्व-सरकार एक संघात्मक व्यवस्था है—विचारकों ने विश्व-सरकार के संघात्मक रूप की कल्पना की है जिसमें विभिन्न राज्य इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे। विश्व-समुदाय की निर्मात्मक इकाइयों के ऊपर एक सर्वोच्च अभिकरण की स्थापना की जाएगी तथा दूसरी ओर सम्प्रभु राष्ट्रों की शक्ति को कम करके उन्हें विश्व-संघ-व्यवस्था के अनावर्तनीय सदस्य का स्तर प्रदान किया जाएगा। विधि-शास्त्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता की स्थापना का प्रयास होगा और निःशस्त्रीकरण द्वारा इकाइयों की शक्ति को इतना कम कर दिया जाएगा कि वे स्थापित सत्ता को चुनौती नहीं दे सकेंगे। नार्मन थॉमस के अनुसार, एक ऐसी सत्ता का निर्माण किया जाना चाहिए जो राष्ट्रों को पूरी तरह न केवल युद्ध मंचालन के यन्त्र से बर्चित करे परन्तु निर्णय लेने के उस यन्त्र को भी हस्तगत कर ले जिससे युद्ध को प्रारम्भ किया जा सकता है।

6. एक अनिवार्य मान्यता—अनिवार्य सरकार का विफल बड़े विस्तार के साथ किया गया है तथापि इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है कि विश्व-सरकार की यह कल्पना साकार हो सकेगी या नहीं। अनेक विचारक इसे एक हवाई किला मानते हैं तो कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो इसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक अनिवार्य और एकमात्र आगामी विकास के रूप में देखते हैं। कुल मिलाकर लॉर्ड का यह मत सन्तुलित है कि केवल इने-गिने समर्थकों को ही निकट भविष्य में विश्व-सरकार का आदर्श प्राप्त होने की आशा है।

विश्व-सरकार की उपयोगिता (The Utility of World Govt.)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् के वर्तमान व्यावहारिक स्वरूप को देखते हुए यह सम्भव नहीं दिखाई देता कि विश्व-सरकार का स्वप्न निकट या सुदूर भविष्य में साकार हो सकेगा, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि यदि विश्व-सरकार की स्थापना हो सके तो यह बहुत उपयोगी बात होगी। इस स्थिति में, भाँगैन्थो के अनुसार, विश्व शान्ति की स्थापना की दिशा में तीन उल्लेखनीय कार्य किए जा सकेंगे—

1. विश्व-सरकार मानव-जाति को वैधानिक व्यक्तित्व प्रदान कर उसकी एकता स्थापित रखेगी।

2. विश्व-सरकार ऐसे अभिकरणों को जन्म देगी और उन्हें गतिशील बनाएगी जिनके द्वारा विश्वव्यापी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकें तथा मानव-जाति के सभी समूहों के विरोधी दावों को कुछ सीमा तक सन्तुष्ट करना सम्भव हो सके।

3. विश्व-सरकार द्वारा ऐसे अभिकरणों की स्थापना की जा सकेगी जो विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का पूरी ताकत से मुकाबला कर सके।

विश्व-सरकार की उपयोगिता पर टिप्पणी करते हुए स्टीवार्ट बोल ने लिखा है कि “सरकार का क्षेत्र शान्ति का क्षेत्र है। शहर, राज्य एवं राष्ट्र में जिस प्रकार शान्ति स्थापित की जाती है उससे तो सभी परिचित हैं। यदि इतने बड़े क्षेत्र पर किसी तरह सरकार की स्थापना की जा सके तो विश्व-सरकार निश्चय ही शान्ति का मार्ग है।”

विश्व-सरकार के समर्थकों का कहना है कि विश्व में शान्ति-स्थापना के लिए द्विमूर्ती कार्यक्रम अपनाने चाहिए—प्रथम, यह प्रयास किया जाए कि विश्व-समाज का कोई भी देश शान्ति भंग करने की इच्छा ही न करे। इसके लिए आवश्यक है कि एक ऐसी सर्वोच्च संस्था का गठन किया जाए जो युद्धप्रेमी राष्ट्रों की अनुचित गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा सके। द्वितीय, राष्ट्रों के पास केवल इतनी ही शक्ति रखी जाए कि वे युद्ध छेड़ने का साहस न कर सकें। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं संघात्मक व्यवस्था में इकाइयाँ आपस में अथवा केन्द्र के साथ प्रायः युद्ध पर नहीं उतर आती। मतभेद रहते हैं और हित टकराते हैं, लेकिन तसवारें नहीं सनबती। कारण यही है कि राज्यों अर्थात् संघीय इकाइयों की तुलना में केन्द्र के पास इतनी प्रबल सैनिक शक्ति होती है कि उसके भय से कोई भी राज्य चल-प्रयोग द्वारा अपने हितों की रक्षा का प्रयास नहीं करता। यदि इसी प्रक्रिया को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाए तो विश्व-शान्ति स्थायी बन सकती है।

विश्व-सरकार की प्रमुख उपयोगिताओं को प्रायः इस प्रकार प्रकट किया जाता है—

1. विश्व-सरकार विश्व-व्यापी भ्रराज्यता को दूर कर सकेगी। कनाड के मत में ‘भ्रराज्यता भय का प्रतीक है’—एक अनियन्त्रित अव्यवस्था का भय। ‘विश्व

में अराजकता है' का आशय दूसरे शब्दों में यह है कि विश्व की स्थिति असहनीय रूप से खतरनाक है। इसके लिए विकल्प यही है कि मानव-जाति दो में से एक को चुन ले—या तो विश्वव्यापी अराजकता को या विश्व-सरकार की स्थापना को अराजकता और सरकार के बीच संदेह विरोध रहता है, अतः विश्व-सरकार की ओर बढ़ाए गए कदम क्रमशः अराजकता को मिटाते चले जाएंगे।

2 विश्व-सरकार ही एकमात्र वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके विश्व को युद्ध की ज्वालाओं से सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वर्गीय श्री नेहरू ने कहा था, “विश्व-सरकार आनी चाहिए और आएगी क्योंकि विश्व की बीमारी का इसके अलावा कोई इलाज नहीं है।” यहुराज्य व्यवस्था के रहने पर तत्सार युद्ध से और युद्ध के खतरों से कभी मुक्त नहीं रह सकता। पर दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि विश्व-सरकार की स्थापना युद्धों की समाप्ति का उपकरण नहीं है। वास्तव में शान्ति तो सभी स्थापित रहती है जब देश परस्पर एकता और सहानुभूतिपूर्ण सम्बन्धों से बँधे रहे। क्या कारण है कि कनाडा और अमेरिका, अमेरिका और ब्रिटेन, ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच निरन्तर मधुर सम्बन्ध चले आ रहे हैं? क्या कारण है कि नार्वे और स्वीडन के सम्बन्ध स्वतन्त्र सम्प्रभु राष्ट्रों के रूप में शान्तिपूर्ण रहे हैं जबकि एक ही सरकार के अधीन होने पर ऐसा नहीं था?

3. विश्व-शान्ति के एकमात्र साधन के रूप में विश्व-सरकार ही सर्वोत्तम विकल्प है। कहा जाता है कि जब सारा विश्व एक हो जाएगा, एक सरकार के अधीन हो जाएगा, तो युद्धों का रूप बदल जाएगा और एकीकृत विश्व-व्यवस्था में युद्ध-युद्ध भी इतने भयावह होंगे कि कोई भी इन्हें छेड़ने का साहस नहीं करेगा। जाफरी सेवर के अनुसार, “किसी भी बड़े भयानक युद्ध की सम्भावना को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि सम्प्रभु आत्म-निर्णायक राज्यों की व्यवस्था को विश्व-सरकार की स्थापना द्वारा स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता।” विश्व-सरकार के समर्थकों का तर्क है कि जब सभी राष्ट्रों की व्यक्तिगत उपलब्धियों को सार्वजनिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया जाएगा तो भेदभाव एवं मनमुटाव के कारण ही नष्ट हो जाएंगे।

4. समर्थकों का तर्क है कि विश्व-सरकार विश्व की प्रगति का प्रतीक है। युद्धों द्वारा न केवल उपलब्धियों का विनाश होता है बल्कि वे तत्त्व और परिस्थितियाँ भी नष्ट हो जाती हैं जिनसे मानव-सम्पत्ता एवं संस्कृति घागे बढ़ती है। हिटलर और मुसोलिनी युद्धों के माध्यम से जर्मनी और इटली को उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँचाना चाहते थे, परन्तु इसका जो परिणाम हुआ उसे जर्मनी और इटली की जनता कभी भूल नहीं सकती। आज के अणु युग में तो युद्धों की बात करना ही आत्मघाती है। विश्व-सरकार चूँकि शान्ति-स्थापना का अत्यन्त प्रभावशील साधन होगी, अतः इसे मानव-सम्पत्ता की प्रगति और समृद्धि का प्रतीक मानना चाहिए। विश्व-सरकार की दूसरी बड़ी उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा विश्व की अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त होने से बचाया जा सकेगा तथा युद्धों और सैनिक तैयारियों पर किए

जाने वाले कल्पनातीत वय को निर्माणात्मक कार्यों में लगाया जा सकेगा। विश्व-सरकार की स्थापना के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की समस्याएँ भी समाप्त हो जाएँगी। जब कोई सम्प्रभु राज्य ही नहीं रहेगा, तो राज्यों के बीच हिंसात्मक युद्ध अथवा संघर्ष होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा।

5. इसके समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के अस्तित्व का जो महत्त्व और उपयोगिता है वही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व-सरकार का होगा। विभिन्न राष्ट्रों में जो भिन्नताएँ, विरोधी स्वार्थ और असमान स्थितियाँ विद्यमान हैं जिनकी प्रायः हिंसात्मक संघर्षों के रूप में अभिव्यक्ति होती है, विश्व-सरकार की स्थापना के बाद उनका हिंसात्मक रूप परिवर्तित होकर सामञ्जस्यपूर्ण बन जाएगा और तब विश्व के प्रति राजभक्ति को विश्व के नागरिक का सबसे प्रधान कर्त्तव्य माना जाएगा। विश्व की एकता को चुनौती देने वाले किसी कार्य को सहन नहीं किया जाएगा तथा केवल उन्हीं हितों, विचारों और राजभक्तियों को प्रचलित रखा जाएगा जो विश्व की एकता को खतरा पैदा न करें। इस प्रकार विश्व-सरकार अन्तर्राष्ट्रीय राजभक्ति को जन्म देगी। राष्ट्रीय सरकारों की भाँति विश्व-सरकार भी न्याय की स्थापना के लिए सचेष्ट होगी। सामान्य हित के विषयों पर समस्त विश्व को समान न्याय प्रदान किया जाएगा और यदि कोई एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्र मिलकर अन्य राष्ट्रों से भिन्न किन्तु सामञ्जस्यपूर्ण किसी उचित व सगत की माँग करते हैं तो विश्व-सरकार उस माँग पर भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान देगी।

राष्ट्रीय सरकार के पास भारी शक्ति होती है जिसके आधार पर वह शान्ति की स्थापना करती है और शान्ति भग करने वाले किसी भी प्रयास को कुचल देती है। इसी प्रकार विश्व-सरकार के पास विपुल शक्ति रहेगी जिसके आधार पर वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं व्यवस्था को बाधा पहुँचाने वाले तत्त्वों का दमन कर देगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व-सरकार की शक्ति के दो रूप होंगे—प्रथम, उसके पास भौतिक-शक्ति केन्द्रित हो जाएगी और दूसरे, विश्व-लोकमत भी उसके साथ रहेगा जिसकी अवहेलना करने का कोई भी राष्ट्र साहस नहीं कर सकेगा।

यह तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए जिस प्रकार राज्य एक आवश्यक साधन है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं व्यवस्था भी विश्व-राज्य एवं विश्व-सरकार की स्थापना से ही हो सकती है। एक राष्ट्र की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तोड़फोड़ के अनेक तत्त्व विद्यमान रहने हैं जिनकी नियन्त्रित करने के लिए एक शक्तिशाली विश्व-सरकार परम आवश्यक है। वहाँ, जानि, धर्म, क्षेत्र एवं अन्य राजनीतिक झगड़ों से विश्व-समाज को छिन्न-भिन्न करने वाले अनेक तत्त्वों की मृष्टि होती है जो शान्ति, संघर्ष और युद्धों का रूप धारण कर लेते हैं। विश्व-सरकार द्वारा इन सभी तत्त्वों पर प्रबुध रखा जाएगा।

विश्व-सरकार के उपाय और साधन (The Ways and Means of World Govt)

विश्व-सरकार की स्थापना में सम्बन्धित विभिन्न विचारों के निष्कर्षों द्वारा प्रस्तुत साधनों को मूल रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

(i) रचनात्मक, (ii) विकासात्मक, एवं (iii) मध्य-स्थिति वाले तीनों ही प्रकार के साधन सरकार की प्रकृति से सम्बन्धित हैं। रचनात्मक साधन के समर्थकों की मान्यता है कि सरकार का निर्माण किया जाता है और यह व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर है कि वे सरकार बनाएँ अथवा न बनाएँ अथवा किस तरीके से बनाएँ। यदि श्रेष्ठ सरकार का निर्माण किया जाना है तो पहले लोगों को समझाना होगा कि यह श्रेष्ठ सरकार है, तत्पश्चात् उन्हें उसके निर्माण के लिए राजी करना होगा। विश्व-सरकार भी इसी ढंग से बनाई जा सकती है। विकासात्मक साधन के समर्थकों के अनुसार सरकार विकास का परिणाम है। यह प्राकृतिक इतिहास का एक भाग है। सरकारें बनाई नहीं जाती बल्कि उत्पन्न होती हैं। मध्य स्थिति वाले की मान्यता है कि राजनीतिक संस्थाएँ यद्यपि मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं और उसी की इच्छा पर प्रभावित रहती हैं, तथापि ये राजनीतिक संस्थाएँ स्वतः ही कार्य नहीं करती—उनके सफल संचालन के लिए कुछ अनुकूल स्थितियों का होना आवश्यक है।

विश्व-सरकार के सम्बन्ध में सरकार की प्रकृति से सम्बन्धित उपर्युक्त साधनों का निष्कर्ष यह है कि—(1) विश्व-सरकार का मनुष्यों द्वारा निर्माण किया जाएगा, (2) विश्व-सरकार की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वह स्वतः ही विकसित होगी, (3) विश्व-सरकार का निर्माण करके उसका विकास किया जाए ताकि वह सफल हो सके। इन तीनों ही विचारों के समर्थकों ने विश्व-सरकार के निर्माण के प्रयासों का अपने-अपने ढंग से वर्णन किया है।

विश्व-सरकार के जन्म से सम्बन्धित विचारकों को फ्रेडरिक हाट्टमैन ने दो भागों में वर्गीकृत किया है—

(क) विकासाशील (Evolutionary) विश्व-सरकार के समर्थक, एवं

(ख) क्रान्तिकारी (Revolutionary) विश्व-सरकार के समर्थक।

प्रथम श्रेणी के विचारक विश्व में सपवाद की स्थापना के लिए समुक्त राष्ट्रसंघ जैसी संस्था को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसमें उनको विश्व-सरकार के प्रारम्भिक रूप की भसक दिखाई देती है। उनका विचार है कि विश्व-सरकार का क्रमशः विकास किया जाता है अर्थात् एक संघ के रूप में विश्व को एकदम परिवर्तित करके विश्व-राज्य का रूप देना और विश्व-सरकार की स्थापना करना चाहते हैं।

विश्व-सरकार की प्राप्त करने के जिन पृथक्-पृथक् उपायों का समर्थन किया गया है, उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—

1. विश्व-विजय द्वारा—विश्व-सरकार में दो बातों का होना अत्यावश्यक है—प्रथम, एक स्थान पर शक्ति का केन्द्रीकरण हो अर्थात् यह एक सर्वोच्च संस्था हो जिसके हाथों में शक्ति का एकाधिकार हो, द्वितीय, विश्व के राष्ट्र सम्प्रभुता से वंचित कर दिए जाएँ। कुछ विचारकों का कहना है कि विश्व-सरकार की स्थापना के इन दोनों पहलुओं की उपलब्धि के लिए विश्व-विजय आवश्यक होगी। विश्व-सरकार के निर्माण का इच्छुक राष्ट्र या राष्ट्र-समूह सैनिक शक्ति का सहारा ले सकते हैं। उसकी सफलताएँ निरन्तर उसे शक्तिशाली बनाती जाएंगी और उसमें धीरे-धीरे

विश्व की शक्ति का केन्द्रीकरण होता चला जाएगा। विजित राष्ट्रों के सम्प्रेमुता रूपी विर्यले दांत टूट जाएंगे और अन्ततोगत्वा विश्व-सरकार की स्थापना हो जाएगी।

विश्व-विजय का यह विचार वस्तुतः घातक है। विश्व-साम्राज्य का स्वप्न देखने वालों की दुर्दशा का इतिहास यह सबक देने को काफी है कि ऐसे गलत मार्ग पर न चला जाए। विश्व-विजय के प्रयासों से तो क्रान्तियों, युद्धों और सघर्षों का जो सिलसिला चलेगा वह सारी मानव-जाति को ही से डूबेगा। आज के आणविक युग में तो विश्व-विजय की बात करना भी भयावह है। पुनश्च, विश्व-विजय द्वारा स्थापित विश्व-राज्य का आधार शक्ति होगी, इच्छा नहीं। इसके अतिरिक्त बुरे साधनों द्वारा हम कभी अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। हिंसा-हिंसा को और युद्ध-युद्ध को जन्म देता है।

2 विश्व-संघ के निर्माण द्वारा—कुछ विचारक स्विट्जरलैंड का उदाहरण प्रस्तुत कर उसी आधार पर विश्व-संघ के निर्माण का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि विश्व के सभी राज्यों को मिलाकर एक सघ में एकीकृत कर दिया जाए और सभी पर स्विस् सविधान जैसी व्यवस्थाएँ लागू कर दी जाएँ, तो विश्व-सरकार का समाधान हो जाएगा।

इस तर्क में कुछ आकर्षण अवश्य है, लेकिन व्यवहार में यह सम्भव नहीं है, क्योंकि—(1) स्विस् कॅन्टनों द्वारा सघ में एकबद्ध होने का एक प्रमुख कारण यह था कि लगभग सभी को एक समान शत्रु से अपनी रक्षा करनी थी, लेकिन विश्व के राष्ट्रों के सम्मुख ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, चन्द्रलोक या मंगल-ग्रह के निवासी पृथ्वी पर आनमण करें तो शायद विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर स्विट्जरलैंड की तरह संघ बना सकते हैं। (2) सघात्मक शासन के बावजूद स्विट्जरलैंड में पूर्ण रूप से आन्तरिक शान्ति नहीं है। वहाँ तीन सौ वर्षों की भ्रष्टाचार में पाँच बड़े धर्म-युद्ध हो चुके हैं। गृह-युद्ध के फलस्वरूप शासन में परिवर्तन होते रहे हैं। (3) सघ-निर्माण के लिए जिन अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा नहीं की जा सकती। पुनश्च, गृह-युद्धों के फलस्वरूप विश्व में जो स्थिति विश्व-संघ के निर्माण के बाद उत्पन्न होगी वह वर्तमान से भी भयंकर होगी।

3. सांविधानिक परिपत्र द्वारा—कुछ क्षेत्रों में यह भी कहा जाता है कि सांविधानिक परिपत्र द्वारा विश्व-संघ का निर्माण किया जाए। इस प्रसंग में संयुक्तराज्य अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है, पर यह सुझाव भी सार्थक नहीं है क्योंकि विश्व-राज्य की स्थापना और स्थापित संयुक्तराज्य अमेरिका की स्थितियों में कोई समरूपता नहीं है। विश्व-राज्य की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक पहले विश्व-समुदाय (World Community) की रचना न कर दी जाए। इसके अतिरिक्त, विश्व के राष्ट्र सम्प्रमुत्ता सम्पन्न हैं जो अपनी इस शक्ति का परित्याग करने को कभी तत्पर नहीं होंगे।

4. विश्व-समुदाय के निर्माण द्वारा—एक कृत्रिम विनाम-प्रणिया द्वारा विश्व-सरकार के निर्माण के समर्थकों का मत है कि पहले विश्व-समुदाय का निर्माण

किया जाए। सभी देशों के निवासियों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सम्बन्धों में पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास किया जाए, ताकि उनमें राष्ट्रीयता की दीवारें तोड़कर अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रचार हो। उनके राष्ट्रीय अभिमान को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान में बदल दिया जाए। ऐसा होने पर विश्व-सरकार की स्थापना सुगम हो जाएगी और स्थापित होने के बाद विश्व-सरकार का सफल संचालन भी सम्भव हो सकेगा : यह विचार भी आकर्षक है, लेकिन व्यवहार में इसकी परिणति सम्भव दिखाई नहीं देती। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि का अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जिस रूप में प्रयोग हो रहा है, वह निराशाजनक है।

विश्व-सरकार की धारणा का मूल्यांकन

(Evaluation of the Concept of World Govt)-

वैचारिक दृष्टि से विश्व-सरकार का विचार नि सन्देह स्वागत योग्य है, तथापि इस विचार का साकार होना सम्भव नहीं दिखाई देता। यह केवल कुछ बुद्धिजीवियों का आन्दोलन है, अन्यथा दुनिया के लोग विश्व-सरकार के विचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे और न ही विश्व के राज्य अपनी सम्प्रभुता का परित्याग करने को सहमत होंगे। व्यक्ति की अन्तिम निराधिक निष्ठा का केन्द्र आज भी राष्ट्र ही है और लोग अपनी इस निष्ठा का परित्याग किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहेंगे। उनकी यह निष्ठा विश्व-सरकार की स्थापना के मार्ग में प्रलम्ब बाधा है। लोग अपने परम्परागत मूल्यों का इस रूप में पुनर्मूल्यांकन करने और अभूतपूर्व नैतिक तथा राजनीतिक क्रान्ति लाने को तत्पर नहीं होंगे जो कि राष्ट्र की धारणा को ही उखाड़कर फेंक दे। जब केवल न्याय के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ही प्रभावी नहीं है, इसी प्रकार जब संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा विश्व-संसद् का विबलप नहीं है और न ही संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व-सरकार का कोई विकल्प माना जा सकता है, तो विश्व-सरकार की स्थापना जैसी बात करना काल्पनिक और बौद्धिक आदर्श ही रहेगा व्यवहार में जिसकी परिणति नहीं हो सकती।

समस्या मूलतः दृष्टिकोण की है। विश्व के प्रति सोचने के दृष्टिकोण में मतभेद का अभाव है। सर्वप्रथम तो विश्व-समाज और उसके प्रति निष्ठा ही नहीं है, अतः विश्व-सरकार की बात करने से पहले दृष्टिकोण में सुधार कर विश्व-समाज के निर्माण की आवश्यकता है।

पुनश्च, अपूर्ण मानव युक्त यह दुनिया अपूर्ण ही रहेगी। युद्ध और शान्ति के तत्त्व इस दुनिया में आरम्भ से रहते आए हैं जो भविष्य में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेंगे। वैचारिक स्तर पर विश्व-सरकार के आदर्श की धीरे प्रगति नि सन्देह उपयोगी है, क्योंकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उदार बनने में सहयोग मिलता है। यह आकांक्षा बुरी नहीं है कि हम विश्व-सरकार की ओर अग्रसर हों।

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ : निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, एवं विश्व जनमत, अन्तर्राष्ट्रीय विकास और संयुक्त राष्ट्रसंघ

(Limitations of National Power : Disarmament, International Morality, World Public Opinion, International Development and U N. O.)

"इस प्रकार प्रत्येक पक्ष ने धारो-धारी से उन शस्त्रों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जो उनके पास नहीं थे, जब तक कि अन्त में भालू नहीं उठ खड़ा हुआ और उसने मधुर युक्ति-युक्तता के स्वर में कहा, कामरेड ! हमें सब चीजों को समाप्त कर देने दो-सब चीजों को सिवाय महान् सर्वव्यापी आतिथ्य के ।"

—तालवेडार डी मेडीसाला

निःशस्त्रीकरण की समस्या उतनी ही पुरानी है जितनी विश्व-शान्ति की समस्या । आज के आणविक युग में तो यह समस्या हमारे जीवन-मरण की समस्या बन गई है । शस्त्रास्त्रों के इस भयावह खतरे के बावजूद शस्त्रीकरण की होड़ इसीलिए जारी है कि आज राष्ट्रो के सम्बन्ध पारस्परिक अविश्वास और दूसरे राष्ट्रों के दूरार्थों के बारे में निरन्तर भय से परिपूर्ण हैं । निःशस्त्रीकरण और शस्त्र-नियन्त्रण आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की उन समस्याओं में से है जो निरन्तर विचार-विमर्श के बावजूद गम्भीरतम रूप धारण किए हुए हैं । अनवरत प्रयासों के बावजूद शस्त्रीकरण की होड़ तेजी से जारी है ।

निःशस्त्रीकरण : अर्थ एवं प्रकार

(Disarmament : Meaning and Types)

अमेरिका की इस्टीम्यूट ऑफ डिफेंस प्रनालिसिस (वाशिंगटन डी. सी.) ने निःशस्त्रीकरण की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है—

"कोई भी एक योजना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निःशस्त्रीकरण के किसी भी एक पहलू—जैसे सख्या, प्रकार, शस्त्रों की प्रयोजन-प्रणाली, उसका नियन्त्रण, उनकी सहायता के लिए पूरक यन्त्रों का निर्माण, प्रयोग व वितरण, गुप्त सूचनाएँ एकत्र करने के संयन्त्र, सेना का गंभीरतात्मक स्वरूप, आदि को नियमित ढंग से सम्बद्ध हो निःशस्त्रीकरण की श्रेणी में आती है ।"

सामान्य अर्थ में निःशस्त्रीकरण वह कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शस्त्रों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम अथवा समाप्त कर देना है। प्रो. मॉर्गेन्थो के अनुसार "निःशस्त्रीकरण से आशय शस्त्रों की बढ़ोतरी समाप्त करने के लिए अथवा सभी शस्त्रों को कम या समाप्त कर देने से है।"

निःशस्त्रीकरण सामान्य (General), स्थानीय (Local), मात्रात्मक (Quantitative), गुणात्मक (Qualitative) कंसा भी हो सकता है। सामान्य निःशस्त्रीकरण में लगभग सभी राष्ट्र सम्मिलित होते हैं जैसे सन् 1932 का विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन। स्थानीय निःशस्त्रीकरण में कुछ ही राष्ट्र भाग लेते तथा प्रभावित होते हैं। मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य सभी प्रकार के शस्त्रों पर नियन्त्रण से है जबकि गुणात्मक निःशस्त्रीकरण के अनुसार किन्हीं विशेष प्रकार के शस्त्रों को कम अथवा समाप्त करने की सिफारिश की जाती है। जब हम पूर्ण निःशस्त्रीकरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रकार के शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने से है।

निःशस्त्रीकरण कार्यक्रम को कतिपय क्षेत्रों में 'शस्त्र-नियन्त्रण' (Arms Control) कार्यक्रम कहा जाता है। यह माना जाता है कि निःशस्त्रीकरण के अनुसार तो राष्ट्रों के पास शस्त्र होने ही नहीं चाहिए। पर पूर्ण निःशस्त्रीकरण कोई नहीं चाहता क्योंकि आन्तरिक व्यवस्था, अस्तित्वशायित्वात् आक्रमण से रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए कुछ शस्त्र सैन्य-बल अपेक्षित है, अतः समस्या 'शस्त्र-नियन्त्रण' (Arms Control) की है, पूर्ण निःशस्त्रीकरण की नहीं। वेजले डब्ल्यू. पोस्वार (Wesley W. Posvar) ने अपने लेख 'The New Meaning of Arms Control' में लिखा है कि "निःशस्त्रीकरण का अभिप्राय सेनाओं और शस्त्रों को घटा देना या समाप्त कर देना है जबकि शस्त्र-नियन्त्रण में वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य युद्ध के सम्भावित और विनाशकारी परिणामों को रोकना (विशेषकर आणविक युद्ध के परिणामों को) है। इसमें सेनाओं तथा शस्त्रों को घटाने या न घटाने का विशेष महत्त्व नहीं है।"

अधिकांश अमेरिकी लेखकों और राजनीतिक विचारकों ने निःशस्त्रीकरण के स्थान पर 'शस्त्र-नियन्त्रण' शब्द का प्रयोग किया है। सोवियत रूस तथा उसके सहयोगी निःशस्त्रीकरण पर ही नहीं बल्कि पूर्ण निःशस्त्रीकरण पर जोर देते हैं। निःशेष दृष्टि से देखने पर शस्त्र-नियन्त्रण ही अधिक सार्थक और व्यावहारिक लगता है जबकि निःशस्त्रीकरण एक ऐसा आदर्श दिखाई देता है जो सोचने, कहने और विवाद करने के लिए मने ही ठीक हो, पर व्यवहार में दुष्प्राप्य है।

निःशस्त्रीकरण अपने आप में समस्या का समाधान नहीं बल्कि एक माध्यम मात्र है जो तेजी सार्थक हो सकता है जबकि वह उद्देश्यपूर्ण तथा योजनाबद्ध हो। शस्त्रीकरण का निषेध अथवा कमी करने के लिए अविश्वास, प्रतिस्पर्धा, शोषण, आदि की भावना के विपरीत अन्धे विकल्प ढूँढ़ने होने और राष्ट्रीय हित की परिभाषाएँ

अधिक विचारपूर्ण ढंग से करनी होगी। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों की सम्भावनाएँ सच्चे मन से खोजनी होंगी अन्यथा मात्र शस्त्रों में कुछ कमी कर देने से निःशस्त्रीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रो. रॉबर्ट बोरी के इस अभिमत से असहमत होना कठिन है कि कोई भी निःशस्त्रीकरण-योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक राष्ट्रों को यह विश्वास न हो जाए कि उनके राष्ट्रीय हित और सुरक्षा निरापद है। इस आश्वासन का एक तरीका, जो सम्भवतः काफी प्रभावशाली होगा, अधिक से अधिक राज्यों को शस्त्र-नियन्त्रण योजनाओं से सम्बद्ध करना है। यद्यपि शस्त्रास्त्रों की बढ़ती हुई विनाशकता स्वयं अपने आप में उन शस्त्रों के प्रयोग को सीमित कर देती है, तथापि प्रयोग की सम्भावना का निषेध नहीं किया जा सकता और आज के आणविक अस्त्रों के प्रयोग का अर्थ है 'महाविनाश'।

निःशस्त्रीकरण : क्यों ?

(Disarmament : Why ?)

शान्ति-स्थापना के लिए

अपने सामान्य और सार रूप में निःशस्त्रीकरण की धारणा में विश्व-शान्ति और सुरक्षा की सम्भावनाएँ निहित हैं। शस्त्रास्त्र एक राष्ट्र की विदेश-नीति को मैनव दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिससे युद्ध और संघर्ष की सम्भावनाएँ सदा जीवित, आग्रत और प्रबल रहनी हैं। श्री कोहन के अनुसार, "निःशस्त्रीकरण द्वारा राष्ट्रों के भय और मतभेद को कम करके शान्तिपूर्ण समझौतों की प्रक्रिया को सुविधाप्रिय तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है।"

निःशस्त्रीकरण और शान्ति के सम्बन्ध में विचार-मलैक्य नहीं पाया जाता। हेडले बुल का तर्क है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता और तनावपूर्ण स्थितियाँ ही युद्ध के वास्तविक कारण हैं, क्योंकि इनसे ही शस्त्रास्त्रों की भीषण प्रतिस्पर्धा शुरू होती है जिसका अन्तिम परिणाम युद्ध और विनाश होना है। प्रो. शूमेन के अनुसार संघर्ष की आगवाही शस्त्रीकरण की होड़ को जन्म देती है और युद्ध की सम्भावना से शस्त्रों में वृद्धि होती है। यह मानना कि शस्त्रों के कारण युद्ध होते हैं, गाड़ी को घोंडे के आगे खड़ा करना है। कुछ विद्वानों का मत है कि शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा में अनिवार्यतः युद्ध नहीं होते और यह भी आवश्यक नहीं है कि निःशस्त्रीकरण से अवश्यम्भावी रूप में शान्ति और सुरक्षा की स्थापना हो जाएगी। मूल समस्या तो अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना की है। किसी राइट का मत एवढम विपरीत है। उनका विचार है कि निःशस्त्रीकरण को शान्ति तथा सुरक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं मान सकते। निःशस्त्रीकरण से तो युद्ध के बार-बार होने की सम्भावना (Frequency) बढ़ जाती है। शस्त्रास्त्रों के अभाव में राज्य दूसरे राज्यों के आक्रामक कार्यों और इरादों का मुकाबला नहीं कर पाते। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध मुख्यतः इसीलिए हुए थे कि बड़े राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा से बचने का प्रयास किया था।

स्पष्ट है कि निःशस्त्रीकरण का विषय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी जटिल और विवादास्पद समस्या है। पर मतभेदों के बावजूद इस तथ्य को नहीं ठुकराया जा सकता कि निःशस्त्रीकरण समय की माँग है और इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्वास के नए द्वार खोले जा सकते हैं। यदि हम अपने व्यवहार में शान्ति के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण बना लें तो निःशस्त्रीकरण के प्रयास बड़ी सीमा तक सफल हो सकते हैं।

आर्थिक कल्याण और पुनर्निर्माण के लिए

निःशस्त्रीकरण के पक्ष में यह आर्थिक तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि 'शस्त्रों की दौड़' के स्थान पर 'शान्ति के लिए दौड़' शुरू होने पर मानव समाज की समृद्धि का मार्ग अधिक प्रशस्त होगा तथा विश्व के औद्योगीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नए युग का सूत्रपात होगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक अध्ययन के अनुसार सेवा पर होने वाला संसार का कुल व्यय 1971 तक 18700 खरब डॉलर तक पहुँच गया था। 1961 से 1971 के बीच दस वर्षों में संसार का रक्षा-व्यय 500 खरब डॉलर से बढ़कर 2000 खरब डॉलर (15000 खरब रुपये) वापिक हो गया जो विश्व की कुल राष्ट्रीय आय का साठे छ. प्रतिशत था। स्टावहोम स्थित प्रसिद्ध शान्ति संस्थान ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि 1980 में संसार भर में हथियारों का भण्डार जमा करने पर 500 खरब डॉलर से भी अधिक मालि प्रतिदिन लगभग डेढ़ खरब डॉलर (लगभग 14 खरब रुपये) खर्च किये गये।¹ संस्थान का आत्मरक्षा के नाम पर रैनिक खर्च में लगातार बढोत्तरी के बावजूद आज हर राष्ट्र अपने आपको सन् साठ वाले दशक की तुलना में वही अधिक खतरे में देखता है। सुरक्षा की जगह असुरक्षा की भावना ही अधिक बढ़ी है।

कुछ क्षेत्रों में कहा जाता है कि निःशस्त्रीकरण के फलस्वरूप भन्दी का दौर शुरू होगा जिसके भीषण परिणाम लोगों को भुगतने पड़ेंगे, साथ ही वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में भी बाधा पहुँचेगी। लेकिन इस प्रकार की आशंकाओं में अधिक बल नहीं। निःशस्त्रीकरण के फलस्वरूप जो रचनात्मक वातावरण बनवेगा, उसमें और वैज्ञानिक तकनीकी विकास की क्षमताएँ अव्यक्त नहीं होंगी, उल्टे आर्थिक समृद्धि के इतने विशाल स्रोत खुल जाएँगे जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अवश्य ही हमें 'शस्त्रीवृत्त अर्थ-व्यवस्था' को 'निःशस्त्रीकरण अर्थ-व्यवस्था' में परिवर्तित करने की समस्या का मुकाबला करना पड़ेगा।

समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये

निःशस्त्रीकरण से विश्व-राज्य के निर्माण की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी, महायुद्ध का सम्भावित खतरा टल जायेगा तथा राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़े आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शीत-युद्ध का ज्वर कम हो जाएगा, आतंक के बादल छट जाएँगे और राष्ट्रों के विवाद बड़ी सीमा तक गोलमेगोल सम्मेलनों में तय होने लगेंगे।

नैतिक वातावरण के निर्माण के लिए

निःशस्त्रीकरण नैतिक रूप से भी आवश्यक है क्योंकि "किसी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य तथा जीवन को रेडियो सक्रिय धूल तथा सामरिक तैयारी द्वारा अनेक खतरों में डाले।" सैद्धान्तिक रूप से नैतिक आधार पर निःशस्त्रीकरण का प्रतिपादन उचित है, लेकिन यथावंचादी राष्ट्रीय राजनीति में इसका विशेष प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए, भारत जैसे शान्तिप्रिय राष्ट्र के प्रति चीन और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए इवतरफा निःशस्त्रीकरण का कोई भी कदम उठाना देश के लिए आरम्भघातक होगा।

आणविक संकट से बचने के लिए

आज के युग में आणविक युद्ध एवं विनाश से बचने का एकमात्र मार्ग निःशस्त्रीकरण अथवा शस्त्रों पर प्रभावशील नियन्त्रण ही है। खतरनाक शस्त्रों पर रोक लगाने तथा उन्हें सीमित कर देने से चाहे मात्रमण रोकें न जा सकें तो भी उनको काम, मर्यादित और अपेक्षाकृत बहुत थोड़ा विध्वंसक बनाया जा सकेगा। निःशस्त्रीकरण के फलस्वरूप प्रथम तो कोई भी राष्ट्र तुरन्त एवं व्यवस्थित रूप से युद्ध छेड़ने में असमर्थ बन जाएगा और दूसरे, राष्ट्रों के मध्य द्वैपपूर्ण सम्बन्धों में कमी हो जाने से राष्ट्रीय हितों के पारस्परिक समायोजन के अनुकूल वातावरण बन जाएगा। नाभिकीय तथा आणविक शस्त्रास्त्र ही आज राष्ट्रों के मनों को घातवित किए हुए हैं। दूसरी ओर यह तर्क भी दिया जाता है कि आज महाशक्तियों की नाभिकीय एवं आणविक शक्ति ने घातक का जो सन्तुलन बना रखा है उसी से विश्व में शान्ति स्थापित है, अन्यथा कभी न। तृतीय महायुद्ध छिड़ गया होता। इस तर्क में वजन है तथापि यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध की निरन्तर सम्भावनाओं और आशकाओं से बचने का रास्ता निःशस्त्रीकरण और शस्त्र-नियन्त्रण का है, शस्त्रीकरण का नहीं।

निष्कर्ष रूप में, आधुनिक परिस्थितियों में विश्व के राष्ट्रों के लिए निःशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाना श्रेयस्कर है। युद्ध और शान्ति का सत्र न कभी निटा है और न कभी सम्भवतः मिट सकेगा, अतः प्रयत्न इसी दिशा में होना चाहिए कि युद्ध की विनाशक-शक्ति घट जाए। इस दृष्टि से नाभिकीय तथा आणविक हथियारों के भावी निर्माण पर ईमानदारी से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और उस प्रकार के उपलब्ध हथियारों को विनष्ट कर देना चाहिए। यह कार्य ज़ोर-जबर्दस्ती न होकर स्वेच्छा में होना चाहिए और इसके लिए सभी राष्ट्रों को ईमानदारी से परस्पर सहयोग करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रीय सदन एवं उपलब्धियों पर शोध करने वाली समिति ने 1960 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि—

"चूंकि महा परमाणु-युद्ध सम्पूर्ण विश्व के लिए विनाशकारी होगा, घन बड़े पैमाने पर निःशस्त्रीकरण के प्रयास किया जाना जरूरी है। यह उगी समय

सम्भव होगा जबकि महाशक्तियाँ आपसी अविश्वास व प्रतिस्पर्धा को गुलाकर परमाणु-शक्ति के उत्पादन परमाणु-प्रस्त्रों के निर्माण, नियन्त्रण एवं विनश्वर पर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एवं प्रतिबन्ध के लिए सहयोग करने को तैयार हो सकें। परमाणु-प्रस्त्रों के परीक्षणों पर नियन्त्रण लगाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।”

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक निःशस्त्रीकरण के प्रयास (Disarmament Measures before the Second World War)

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक के निःशस्त्रीकरण-प्रयासों को दो शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है—

- (ख) राष्ट्रसंघ के बाहर किए गए निःशस्त्रीकरण के प्रयास एवं
- (ख) राष्ट्रसंघ द्वारा निःशस्त्रीकरण के प्रयास

राष्ट्रसंघ के बाहर किए गए निःशस्त्रीकरण-प्रयास

विगत लगभग 150 वर्षों से निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी विभिन्न प्रयास होते रहे हैं। 1817 में ब्रिटेन तथा अमेरिका के मध्य हुए रूस-बगोट सम्मेलन द्वारा अमेरिका-कनाडा को विसैन्यीकृत घोषित किया गया था, 1831 में फ्रांस में कई बार नेपोलियन तृतीय ने घोर 1870 में ब्रिटेन ने दूसरे देशों के सम्मुख सामान्य निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव रखे थे, लेकिन 1899 का हेग सम्मेलन ही ऐसा प्रथम महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें सभी बड़ी शक्तियों सहित 28 राष्ट्रों ने भाग लिया और हथियारों में कमी करने का प्रयास किया। प्रथम हेग सम्मेलन में विपैली और दम घोटने वाली रौसों से युक्त अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए नियम बनाए गए। दमदम बुलैट्स (शरीर में जाकर फटने वाली गोलियों) के प्रयोग को निषिद्ध करने के लिए भी नियम बनाए गए। 1907 के द्वितीय हेग सम्मेलन में भी इन्हीं प्रयामों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। दोनों ही हेग सम्मेलनों में निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका तथापि युद्ध-संचालन और युद्ध में बर्बरता कम करने सम्बन्धी नियमों की आधुनिकता आवश्यक रखी गई।

प्रथम महायुद्ध के विनाश के बाद निःशस्त्रीकरण के लिए पुनः उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ। राष्ट्रपति विल्सन ने शान्ति सन्धियों के लिए 14 सूत्री प्रस्ताव में यह सुझाव दिया कि शस्त्रीकरण उस सीमा तक किया जाए जितना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। इस सुझाव को राष्ट्रसंघ के विधान में भी स्वीकार किया गया।

राष्ट्रसंघ के बाहर दो महायुद्धों के बीच निःशस्त्रीकरण की दिशा में जो प्रयत्न किए गए उनमें उल्लेखनीय थे—वाशिंगटन सम्मेलन (1921-22), जेनेवा नौ सैनिक सम्मेलन (1927), लन्दन नौ सैनिक सम्मेलन (1930), एवं द्वितीय लन्दन नौ सैनिक सम्मेलन (1935)।

वांशिंगटन-सम्मेलन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली के अतिरिक्त चीन, पोलैण्ड, पुर्तगाल आदि भी शामिल हुए, दो महायुद्धों के बीच हुए निःशस्त्रीकरण-सम्मेलनों में सबसे महत्वपूर्ण और सफल सम्मेलन था। इसने युद्धोपेतों के निर्माण की तात्कालिक प्रतियोगिता को नियन्त्रित किया। ब्रिटेन, अमेरिका और जापान द्वारा पूर्वी एशिया में नए नौ-सैनिक अड्डे बनाने या प्राप्त करने का निषेध किया गया और वर्तमान अड्डों में अधिक किलेबन्दीय या शस्त्रीकरण पर रोक लगाई गई। इस सम्मेलन में हुए समझौते का यह सुपरिणाम निकला कि नौ-सैनिक प्रतियोगिता लगभग दस वर्षों तक के लिए रुक गई अथवा एकदम मंथर पड़ गई तथा विशाल जमी जहाजों पर होने वाला भारी व्यय भी कुछ वर्षों के लिए टल गया। छोटे जहाजों के सम्बन्ध में कोई समझौता न हो पाने से लड़ाकू जहाज-निर्माण की प्रतिस्पर्धा चलती रही। कुछ ही वर्षों में सम्मेलन के आशाजनक परिणाम निराशा में बदल गए और महाशक्तियों ने विभिन्न आधारों पर अपनी नौ-सैनिक शक्ति में अधिक कटौती करने में असमर्थता प्रकट की।

1927 में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का जेनेवा में सम्मेलन हुआ। इसमें तीनों राष्ट्रों के विख्यात नौ-सेनापति एवं नौ-विशेषज्ञ सम्मिलित हुए जिनसे यह आशा करना व्यर्थ था कि वे नौ-सैन्य शक्ति घटाने के सच्चे प्रयास करेंगे। काफी विचार-विमर्श और वाद-विवाद हुआ, पर अन्त में अगस्त, 1927 में सम्मेलन की असफलता घोषित कर दी गई। यह निःशस्त्रीकरण-प्रयासों की एक गम्भीर पराजय थी जिसकी काली छाया राष्ट्रसंघ पर तो पड़ी ही, जिससे एंग्लो-अमेरिकी सम्बन्ध भी खराब हो गए। अमेरिका भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उसे अपनी नौ-सेना में इतनी वृद्धि करनी चाहिए जिससे अन्य राष्ट्र भयभीत होकर अपनी नौ-सैनिक शक्ति सीमित करने को बाध्य हो जाएँ।

1930 में अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन आदि राष्ट्रों का एक नौ-सैनिक सम्मेलन लन्दन में हुआ जिसमें एक सन्धि द्वारा नौ-सैनिक शक्ति-नियन्त्रण की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गईं। जापान को इन व्यवस्थाओं से विशेष आघात पहुँचा और आगे चलकर उसने स्पष्ट कह दिया कि उसे भी ब्रिटेन एवं अमेरिका की तुलना में समान नौ-सैनिक सुविधा दी जाए, अन्यथा वह स्वयं को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से बाधित नहीं समझेगा। चूँकि ब्रिटेन और अमेरिका ने जापानी माँग को स्वीकार नहीं किया, अतः 1937 में जापान ने इस मामले में पूर्ण स्वतन्त्रता ग्रहण कर ली। उधर हिटलर के उत्कर्ष एवं अन्त्यान्य कारणों से अन्य महाशक्तियों को भी अपनी नौ-सैनिक शक्ति का विस्तार करने की भाव्य होना पड़ा और इस प्रकार लन्दन-सन्धि की व्यवस्थाएँ अन्त में केवल कागज पर ही रह गईं।

नौ-सेना के निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में अन्तिम प्रयास के रूप में दिगम्बर, 1935 में द्वितीय लन्दन सम्मेलन आरम्भ हुआ जिसमें सभी महाशक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन में जापान ने ब्रिटेन और अमेरिका के बराबर जल सेना रखने की माँग की। चूँकि इस प्रस्ताव को मानने के लिए ब्रिटेन एवं अमेरिका सहमत नहीं

हुए, अतः 15 जनवरी, 1936 को जापान सम्मेलन से पृथक् हो गया। एबीसीनिया-मंकट के कारण इटली ने भी सम्मेलन का परित्याग कर दिया। जापान और इटली के सहयोग से बंचित होने पर भी सन्धि-वार्ता चलती रही और अन्त में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी नौ-सैनिक शस्त्रों पर संकुश लगाने व सामुद्रिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 'नौ-सैनिक शस्त्रों के परिसीमन की सन्धि' पर 25 मार्च, 1936 को हस्ताक्षर किए। इटली और जापान द्वारा सन्धि का बहिष्कार हो जाने के कारण इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रह गया।

राष्ट्रसंघ द्वारा किए गए निःशस्त्रीकरण-प्रयास

राष्ट्रसंघ ने भी निःशस्त्रीकरण की दिशा में काफी प्रयास किए थे, पर अन्ततोगत्वा असफलता ही हाथ लगी। प्रसविदा के आठवें अनुच्छेद के दूसरे प्रकरण में उल्लेख था कि "प्रत्येक राज्य की भौगोलिक व्यवस्था एवं परिस्थितियों का लेखा रख कर परिपक्व विभिन्न सरकारों द्वारा विचार और कार्यवाही के लिए शस्त्रास्त्रों में कमी की योजना बनाए।"

इस व्यवस्था के अनुपालन में 1920 में अस्थायी मिश्रित आयोग (Temporary Mixed Commission) ने स्थायी आयोग (Permanent Advisory Commission) के सहयोग से, अक्टूबर, 1924 में अस्तित्वहीन होने से पूर्व, निःशस्त्रीकरण समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्न किए। अन्तिम प्रयत्न में पारस्परिक सहायता-सन्धि का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसमें निःशस्त्रीकरण से सामूहिक सुरक्षा को मूल आधार माना गया। समस्या के हल के लिए अनेक सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जिनमें कहा गया कि कोई भी निःशस्त्रीकरण की योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वह व्यापक रूप से सब पर लागू न हो और अनेक राज्य अपने शस्त्रास्त्रों में तब तक कमी करने की स्थिति में नहीं आ सकते जब तक कि उन्हें सुरक्षा के लिए पर्याप्त आश्वामन न मिल जाए। यह सचेत दिया गया कि ऐसे आश्वामनों की व्यवस्था पारस्परिक प्रतिरक्षात्मक सन्धियों द्वारा की जा सकती है जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य को सुरक्षा आश्वामन देते हुए विश्वास दिलाए कि आक्रमण की स्थिति में प्रत्येक राज्य आक्रान्त देश की रक्षा के लिए युद्ध करेगा।

पारस्परिक सहायता-सन्धि के प्रारूप (Draft Treaty of Mutual Assistance) की सफलता प्राप्त नहीं हुई और तब मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से सुरक्षा और सुरक्षा से निःशस्त्रीकरण का नया मार्ग ढूँढा गया। कोई सफलता हाथ न लगने पर अक्टूबर, 1924 में अस्थायी मिश्रित आयोग ने काम करना बन्द कर दिया और 1925 में एक 'प्राारम्भिक आयोग' (Preparatory Commission) का गठन किया गया जिसने दिसम्बर, 1930 में निःशस्त्रीकरण की योजना का एक अस्थायी प्रारूप-प्रस्ताव (Dummy Draft Convention) पास कराने की सफलता अर्जित की। इसकी मुख्य व्यवस्थाएँ थी—बजट द्वारा स्पष्ट युद्ध-सामग्री पर नियन्त्रण किया जाए, अनिवार्य सैनिक सेवा की अवधि घटाई

जाए, सैनिकों की संख्या बिना किसी भेदभाव के नियन्त्रित की जाए, रासायनिक एवं कीटाणु-युद्धों को रोका जाए, आदि। इस प्रस्ताव में प्रशिक्षित एवं सुरक्षित सेनाओं, स्थल तथा जन-सेनाओं के शस्त्रास्त्रों अथवा वायु सेना की सामग्री के व्यय पर कोई प्रतिबन्ध या नियन्त्रण नहीं सुझाया गया था। प्रारम्भिक आयोग के प्रस्ताव का व्यावहारिक मूल्य बहुत कम था। फरवरी, 1932 में होने वाले नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन ने उसका उपयोग भी नहीं किया, तथापि आयोग के श्रम का यह परिणाम अवश्य निकला कि नि.शस्त्रीकरण सम्बन्धी वे मूलभूत मतभेद प्रकाश में आ गए जिनका समर्थन सम्मेलन को करना पड़ता था।

प्राथमिक आयोग के प्रस्तावों को मुख्य आधार मानकर जेनेवा में फरवरी, 1932 में नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें अनेक नए सुझाव प्रस्तुत किए गए। लीग के अधीन एक पुलिस-शक्ति के गठन की सिफारिश की गई जिसका बमबर्पकों पर एकाधिकार हो। आक्रामक को कठोरता से दण्ड देने एवं पक्ष-निर्णय को आवश्यक बनाने की बात कही गई। किमी. अनसुलझे विवाद पर अन्तिम रूप से कानूनी निर्णय देने के लिए जोर दिया गया। अस्त्र-शस्त्र एवं मानव-शक्ति के जितने भी रूपों पर विवाद हुआ उनमें सबसे अधिक सहमति रासायनिक एवं जीवाणु हथियारों की आक्रमणकारी प्रकृति पर हो सकी। यह सम्मेलन अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इसका एक कारण तो यह था कि पश्चिमी देशों को मोक्षित रूस की भावी विदेशी नीति के बारे में डर था। दूसरा, फ्रांस व जर्मनी किसी भी बात पर एक मत नहीं हो सके थे।

अन्तिम परिणाम के रूप में नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन सर्वथा असफल रहा। अक्टूबर, 1933 में जर्मनी ने सम्मेलन से वहिर्गमन की घोषणा कर दी और एक सप्ताह बाद ही उसने राष्ट्रसंघ को भी छोड़ दिया। मार्च, 1935 में जर्मनी ने वर्साय-सन्धि के नि.शस्त्रीकरण से सम्बन्धित उपबन्धों को खुले रूप से अप्रभावकारी घोषित कर दिया। इस सम्पूर्ण स्थिति को चित्रित करते हुए शूमा ने लिखा है कि "राष्ट्रसंघ द्वारा ससार में नि.शस्त्रीकरण के प्रयासों का आरम्भ जर्मनी के एकपक्षीय नि.शस्त्रीकरण से हुआ था और जर्मनी के एकपक्षीय पुनः सशोधन से इन प्रयासों का अन्त हो गया। यूरोप की सामूहिक बुद्धि सुरक्षा-प्राप्ति में असफल हो जाने के उपरान्त, आत्मघात की तैयारियों में लग गई।"

द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में नि.शस्त्रीकरण के प्रयास

(The Second Post-war Period Disarmament Talks)

द्वितीय महायुद्ध के बाद के नि.शस्त्रीकरण-प्रयासों को हम मोटे रूप में दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—प्रथम भाग के अन्तर्गत उन समय तक की बातें हैं सम्मिलित की जा सकती हैं जब केवल अमेरिका ही अणु-बम का स्वामी था, द्वितीय भाग का आरम्भ तब से माना जा सकता है जब मोक्षित संघ ने भी अणु-बम का निर्माण कर लिया। नि.शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों ही तैमो में विरोधी दृष्टिकोण मिलता है और इन दिशा में किए जाने वाले प्रयासों

का क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ भी है तथा निजी वार्ताएँ भी। द्वितीय महायुद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण की दिशा में जो भी प्रयास किए गए हैं उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों में व्यक्त करना उपयुक्त होगा—

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में निःशस्त्रीकरण की व्यवस्था

संघ के चार्टर में निःशस्त्रीकरण को महासभा और सुरक्षा-परिषद् दोनों ही की कार्य सूची में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 11, 26 एवं 47 में तत्सम्बन्धी व्यवस्थाएँ हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने प्रारम्भ से ही निःशस्त्रीकरण की समस्या पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जनवरी, 1946 में संघ द्वारा अणु-शक्ति आयोग (Atomic Energy Commission) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य एक ऐसी योजना का निर्माण करना था जिसके अन्तर्गत राष्ट्र परमाणु-शक्ति के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में रखने तथा अणु-शक्ति का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने को सहमत हो सकें और आणविक अस्त्रों के प्रयोग व उत्पादन पर पूरा नियन्त्रण लगाया जा सके। अणु-शक्ति आयोग को वांछित सफलता नहीं मिली। अतः दिसम्बर, 1946 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका आशय था कि अणु-शक्ति आयोग अपने कार्य में तीव्रता लाए और सुरक्षा-परिषद् शीघ्रतापूर्वक शस्त्रों के घटाने तथा उनका नियमन करने की व्यावहारिक योजनाएँ बनाए। जोध्र ही परिषद् द्वारा 'परम्परागत शस्त्र आयोग' (The Commission for Conventional Armaments) गठित किया गया जिसका कार्य केवल परम्परागत शस्त्रों को सीमित एवं नियमित करने के प्रस्ताव रखना ही था, अणु-शस्त्रों और विनाश के व्यापक साधनों से इसका सम्बन्ध नहीं था।

दोनों आयोगों की स्थापना भी हो गई, महाशक्तियों द्वारा विभिन्न प्रस्ताव भी रखे गए, लेकिन सभी प्रयासों का नतीजा कुल मिलाकर शून्य रहा। शान्ति की दिशा में बढ़ने के विपरीत उल्टे इन प्रयासों ने शीतयुद्ध को प्रोत्साहन दिया। अमेरिका ने एक अन्तर्राष्ट्रीय आणविक विकास-संस्था के निर्माण का सुझाव रखा जो परमाणु-शक्ति के उत्पादन से सम्बन्धित कच्चे माल पर भी नियन्त्रण लगाए। सोवियत रूस ने सुझाव दिया कि वर्तमान परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर दिया जाए और तत्पश्चात् सुझावों को कार्यान्वित किया जाए। महाशक्तियों के पारस्परिक विरोधी रुख के फलस्वरूप निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी।

1947 से 1954 तक कई छुट्ट-पुट्ट प्रयास हुए। सन् 1954 के प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति एजेंसी (International Atomic Energy Agency) अस्तित्व में आई जिसने एक पंचराष्ट्रीय उप-समिति की स्थापना की। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और रूस इसके सदस्य बने। अनेकों बैठकों के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल पाया। स्थिति यही रही कि एक पक्ष की ओर से निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव आते और दूसरे पक्ष की ओर से टुकरा दिए जाते।

जेनेवा-सम्मेलन, 1955 से 1960 तक

जुलाई, 1955 में जेनेवा में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस का सम्मेलन हुआ जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन हॉवर ने 'उन्मुक्त आकाश योजना' (Open Skies Plan) प्रस्तावित की। इसका आशय था कि अमेरिका और रूस दोनों ही अपने सैनिक बजट, उत्पादन, वर्तमान शक्ति एवं उसके विकास की सम्भावनाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचना दें तथा परस्पर जाँच एवं निरीक्षण के लिए सहमत हों। एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए। सोवियत प्रधान मंत्री बुल्गानिन ने अमेरिकी योजना को अस्वीकार करते हुए अपना यह प्रस्ताव रखा कि निःशस्त्रीकरण को क्रियान्वित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण-अभिकरण की स्थापना की जाए और उसे जाँच में निरीक्षण का कार्य सौंपा जाए, सभी देशों से विदेशी सैनिक अड्डों को समाप्त कर दिया जाए, आणविक-शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए और परम्परागत शस्त्रों में निश्चित कटौती की जाए।

जेनेवा-सम्मेलन असफल रहा। जून, 1956 में संयुक्त राष्ट्रसंघीय निःशस्त्रीकरण आयोग की उप-समिति की बैठक में रूस ने त्रिसूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया— (1) दो वर्ष के लिए आणविक परीक्षण बन्द कर दिए जाएँ, (2) इस प्रतिबन्ध को लागू करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग बँठाया जाए, एवं (3) आयोग सहित रूस, अमेरिका और ब्रिटेन प्रशान्त महासागर में नियन्त्रण चौकियाँ स्थापित करें। रूसी प्रस्ताव पश्चिमी राष्ट्रों को मान्य नहीं हुए। लन्दन-सम्मेलन की असफलता घोषित कर दी गई।

नवम्बर, 1957 में निःशस्त्रीकरण आयोग का विस्तार किया गया। अगस्त, 1957 में रूस ने अन्तर्महाद्वीपीय (ICBM) के सफल परीक्षण की घोषणा करके और अक्टूबर, 1957 में एक कृत्रिम उपग्रह (Sputnik) छोड़कर पश्चिमी जगत् की स्तब्ध कर दिया।

दोनों पक्षों की ओर से निःशस्त्रीकरण-प्रस्तावों को प्रस्तुत और अस्वीकृत करने का प्रेम जारी रहा। फरवरी, 1958 में रूसी प्रधान मंत्री बुल्गानिन ने एक योजना प्रस्तावित की जिसके मुख्य पहलू ये थे— (1) अणु-बमों के परीक्षणों को बन्द किया जाए, (2) अमेरिका, रूस व ब्रिटेन आणविक शस्त्रों का परित्याग करें, (3) जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में विदेशी सेनाओं को घटाया जाए, (4) नाटो तथा वारसा पैक्ट के देशों में अनाक्रमण सम्झौता हो, एवं (5) आर्थिक आक्रमणों को रोकें जाए। यह योजना निष्फल गई। मार्च, 1958 के लगभग पोलैण्ड के विदेश मंत्री ने 'रापाकी योजना' (Rapacki Plan) प्रस्तुत की जिसमें यूरोपीय सुरक्षा और शान्ति हेतु पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अणु-विहीन क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया। यह प्रस्ताव भी निष्फल रहा। मार्च, 1958 में सुप्रीम सोवियत के एक प्रस्ताव में कहा गया कि सोवियत संघ दस आणा से भी प्रचार के आणविक परीक्षण बन्द कर रहा है कि

अन्य देश भी इसका अनुसरण करेंगे, किन्तु यदि दूसरे देशों द्वारा आणविक परीक्षण बन्द नहीं किए गए तो वह अपने परीक्षण पुनः प्रारम्भ कर देगा। अमेरिका द्वारा कहा गया कि यदि उसे रूसी परीक्षाओं के बन्द करने का निश्चय हो गया तो वह भी अपने परीक्षण बन्द करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा। अक्टूबर, 1958 में जेनेवा-सम्मेलन में निःशस्त्रीकरण पर अनेक प्रस्ताव पेश हुए, पर कोई उपयोगी समझौता नहीं किया जा सका।

1959 में रूसी प्रधान मन्त्री लु. श्चेव ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में पूर्ण निःशस्त्रीकरण का एक प्रस्ताव रखा कि चार वर्ष की अवधि में सभी राज्य पूर्ण निःशस्त्रीकरण कर लें ताकि किसी राज्य के पास युद्ध करने का कोई साधन न रह जाए। साथ ही उन्होंने एक आंशिक निःशस्त्रीकरण की योजना भी प्रस्तावित की जिसमें कहा गया कि नाटो-सदस्यों तथा पश्चिमी राज्यों के साथ चारसा पैक्ट के सदस्यों की अनाक्रमण नग्न सम्पन्न हो, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रामक आक्रमण रोकने के बारे में समझौता करे, मध्य यूरोप में अणु-प्राणु-विहीन क्षेत्र कायम किया जाए आदि। रूसी प्रस्ताव का सब देशों ने स्वागत किया, लेकिन पश्चिमी शक्तियों द्वारा इसे मजबूत का विपन्न बना दिया गया और इस प्रकार गतिरोध बना रहा। सन् 1960 में भी जेनेवा-सम्मेलन हुआ, पर असफल रहा।

जुलाई, 1960 से 1977 तक

जून, 1960 में दस राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन भग हो जाने के कुछ ही माह बाद मोबेनस रुन ने 50 महाजन शक्ति के अणु-बम का परीक्षण किया। नवम्बर, 1961 में महासभा ने यह भारतीय प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि आणविक परीक्षणों पर जब तक कोई समझौता न हो जाए तब तक इनको बन्द ही रखा जाए। मार्च, 1962 में विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन को निःशस्त्रीकरण-प्रस्तावों में कोई सफलता नहीं मिली। इसी समय जेनेवा में निःशस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन हुआ जिसमें भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि आणविक परीक्षणों का पना लगाने के लिए तटस्थ राष्ट्रों के स्टेसन कायम किए जाएँ। रूस ने प्रस्ताव रखा कि दोनों ही पक्ष यह समझौता कर लें कि दूसरे देशों की भूमि पर तीन महान् आणविक शक्तियाँ आणविक-घड़ों कायम नहीं करेंगी। सम्मेलन में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का महत्व केवल कागजी रहा।

कैनेडी और लु. श्चेव के प्रयत्नों से निःशस्त्रीकरण-वार्ता में कुछ प्रगति हुई और मास्को में ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ने 15 जुलाई, 1963 को 'सीमित परमाणु-प्रतिद्वन्द्व-सन्धि' पर हस्ताक्षर किए। 10 अक्टूबर, 1963 से सन्धि लागू हुई। उस समय तक लगभग 100 राष्ट्र इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर चुके थे। सन्धि के अन्तर्गत तीनो देशों ने स्वीकार किया कि वे अपने क्षेत्र के अन्दर बाह्य अन्तरिक्ष, प्रादेशिक तथा महायुद्ध या वायुमण्डल में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे। सन्धि असंमित अवधि के लिए की गई तथापि हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों को अधिकार दिया गया कि वे उस समय स्वयं को इस सन्धि की बाध्यताओं से

मुक्त रख सकते हैं जब वे समझें कि सन्धि से सम्बन्धित कोई ऐसी असामान्य घटना घटी है जिससे सम्बन्धित देश का सर्वोच्च हित संकट में पड़ गया है। सन्धि में अन्य सदस्यों को सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था की गई बशर्ते कि वे इसकी मौलिक धाराओं से सहमत हों। इस सन्धि में भूमिगत परीक्षणों पर प्रतिबन्ध की बात नहीं की गई क्योंकि भूमिगत परीक्षणों की जाँच के लिए घटना-स्थल पर जाना अनिवार्य होता है जिससे राज्य की प्रादेशिक सार्वभौमिकता का उल्लंघन होता है।

परमाणु-परीक्षण-प्रतिबन्ध-सन्धि ने खुले तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बात-चीत का स्वस्थ वातावरण तैयार किया पर माघ, 1964 में जेनेवा-निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का कोई अच्छा फल नहीं निकला। कुछ ही दिनों बाद चीन ने अपने प्रथम अणु-बम का परीक्षण कर सन् 1963 के जेनेवा-समझौते की उपेक्षा की। जुलाई, 1965 में जेनेवा में निःशस्त्रीकरण आयोग की बैठक पुनः बुलाई गई, लेकिन आयुधों को नियन्त्रित करने के तरीकों पर इतने मौलिक मतभेद थे कि कोई फल नहीं निकला।

निःशस्त्रीकरण की दिशा में एक आंशिक सफलता तब मिली जबकि रूस व अमेरिका के बीच 1968 की परमाणु-अस्त्र प्रसार-निरोध सन्धि (The Non-Proliferation Treaty, 1968) मौलिक रूप से हुई, अन्य राज्य—खास तौर पर यूरोप के राज्य—इससे आश्वस्त नहीं थे। सारांशतः उसकी मूल बातें ये थी—(1) परमाणु-अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र, परमाणु-अस्त्र-विहीन राष्ट्रों को परमाणु-अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे, (2) हस्ताक्षरकर्त्ता परमाणु-अस्त्र बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, (3) हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों को असंनिध कार्यो के लिए परमाणु-शक्ति का विकास करने की पूरी छूट रहेगी।

अनेक राष्ट्रों की आपत्तियों के बावजूद जून, 1968 में मयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा ने सन्धि पर अपनी स्वीकृति दे दी। इस सन्धि का बहुत से राष्ट्रों ने स्वागत नहीं किया। सन्धि की सबसे बड़ी कमी यह है कि एक ओर तो यह प्रतिबन्ध है कि जो राष्ट्र परमाणु-बम नहीं बना पाए हैं वे भविष्य में भी इस ओर कदम नहीं उठाएँगे और दूसरी ओर उन्हें परमाणु आक्रमण से बचने के लिए आशवासन दिया है कि मयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा अणु-प्रायुधों से उनकी सहायता की जाएगी जिसका निर्णय सुरक्षा-परिषद् करेगी। स्पष्ट है कि सुरक्षा-परिषद् के किसी भी स्थायी सदस्य को किसी प्रस्ताव के वीटो करने का अधिकार है। इनके अनिश्चित राष्ट्रों ने 'आक्रमण' शब्द की व्याख्या नहीं की है। अतः यह भ्रम बने रहने की सम्भावना है कि परिषद् जिस हानन में किसी आक्रमणकारी समझेगी। भारत ने सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए। कारण स्पष्ट है कि उसे परमाणु-अस्त्र-सम्पन्न चीन से जबरदस्त खतरा है और सन्धि इस खतरों को दूर नहीं कर सकती।

1968 में परमाणु-अस्त्र विरोधी सन्धि के उपरान्त 1972 के प्रारम्भिक चरण तक निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की जा सकी।

मई, 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति नक्सन ने मास्को की यात्रा की और 'रुम-अमेरिका परमाणु परिसीमन सन्धि, 1972' सम्पन्न हुई। इस पचवर्षीय सन्धि में, जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिरूप प्रमाणित होने पर किसी भी पक्ष द्वारा 6 महीने के नोटिस पर रद्द की जा सकती है, स्वीकार किया गया कि—(1) नए अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण नहीं किया जाएगा, (2) कोई भी पक्ष हल्के या पुरानी किस्म के भू-प्रक्षेपास्त्र-स्थलों को सुधार कर भारी अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के लिए योजना नहीं बनाएगा, (3) दोनों पक्ष पनडुब्बियों के प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपकों और प्रक्षेपास्त्रयुक्त आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण नहीं करेंगे, हालांकि निर्माणाधीन पनडुब्बियों का काम पूरा करने की छूट रहेगी, (4) सन्धि की व्यवस्थाओं को प्यान में रखते हुए आक्रामक प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपकों का आधुनिकीकरण करने अथवा स्थानांतरण अस्त्र बनाने का अधिकार दोनों देशों को रहेगा, एवं (5) सन्धि के अनुपालन की जांच के लिए हर एक राष्ट्र केवल वे ही विधियाँ अपनाएगा जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मान्य सिद्धान्तों के अनुरूप हैं।

वास्तव में इस सन्धि से भी निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। श्रीमती गाँधी की टिप्पणी थी कि अस्त्र-परिसीमन अपने आप में सही चीज है, लेकिन दुनिया के आकी हिस्सों में शान्ति-स्थापना की दिशा में इसमें कोई सहयोग नहीं मिलता। रूस और अमेरिका दोनों को यह आश्वासन देना चाहिए कि परमाणु-अस्त्रों का उपयोग परमाणु अस्त्र-विहीन देशों के खिलाफ नहीं किया जायगा। इसके अलावा सन्धि इतनी आशिक है कि परमाणु-अस्त्रों पर खर्च होने वाली राशि में कमी आने की कोई संभावना नहीं है।

मास्को में परमाणु परिसीमन सन्धि के सम्पन्न होने के बाद सन् 1973 के मध्य तक निःशस्त्रीकरण और अणु-शक्ति के परिसीमन के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी, उल्टे निःशस्त्रीकरण-प्रयासों को ठेस ज़रूर पहुँची। 27 जून, 1973 को चीन से एक और परमाणु-विस्फोट किया जो 2 मेगाटन टी. एन. टी. शक्ति का था।

सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 27 जून से 3 जुलाई, 1974 तक तीसरी शिखर-वार्ता हुई। 3 जुलाई, 1974 को एक दस वर्षीय आणविक आयाध-परिसीमन समझौता हुआ उसे 31 मार्च, 1976 से लागू किया जाना निश्चित किया गया। समझौते के अनुसार दोनों ने 150 किलो टन से अधिक के भूमिगत आणविक परीक्षणों को रोकने तथा अपने प्रक्षेपास्त्रों पर नई सीमा लगाने का निश्चय प्रकट किया। यह तय किया गया कि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किए गए विस्फोट इस आशिक प्रतिबन्ध-व्यवस्था की परिधि में नहीं आएँगे। नए समझौते के अन्तर्गत दोनों पक्ष अपनी-अपनी प्रक्षेपास्त्र-व्यवस्था को 3 अक्टूबर, 1977 से 2 अक्टूबर, 1978 के बीच एक बार और उसके उपरान्त पाँच वर्ष में एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेंगे। यह कार्य परस्पर सूचना के आदान-प्रदान के अन्तर्गत ही किया जा सकेगा। 7 जून, 1976 को एक नई धारा जोड़कर इस सन्धि

को अधिक लाभकारी बना दिया गया और स्थल का निरीक्षण करने पर दोनों देश सहमत हो गए।

1977 में महाशक्तियों में हथियारों की होड़ एक बार फिर शुरू हो गई। अमेरिका ने बी-1 बमवर्षक न बनाने का निर्णय तो लिया साथ ही यह निर्णय भी लिया कि वह 'कूज' प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करेगा। इससे पहले उसने न्यूट्रान बम का परीक्षण भी किया था। सोवियत सघ ने इन नए हथियारों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे नए हथियारों के निर्माण से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जटिलताएँ ही पैदा होगी तथा सोवियत सघ और अमेरिका के बीच सामरिक हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी वार्ता में गतिरोध उत्पन्न होगा।

सोवियत अक्टूबर क्रान्ति की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 नवम्बर को ब्रेझ्नेव ने यह प्रस्ताव किया कि सभी देश एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत परमाणु अस्त्रों का निर्माण एक साथ रोक दें। उन्होंने यह आग्रह भी किया कि एक निश्चित अवधि के लिए न केवल सभी प्रकार के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय बल्कि साथ ही शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किए जाने वाले परमाणु विस्फोटों को भी स्थगित किया जाए। ब्रेझ्नेव ने यह सुझाव दिया कि जिन देशों के पास परमाणु अस्त्रों के भण्डार हैं वे उसमें धीरे-धीरे कटौती करें और अन्त में उसे बिल्कुल समाप्त कर दें। सोवियत राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव से कुछ दिन पहले ही जापान ने यह आग्रह किया था कि परमाणु अस्त्र-निरोध सन्धि को सार्थक बनाने के लिए सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए क्योंकि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए और नैतिक उद्देश्यों से किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों में भेद करना तबनीकी दृष्टि में सम्भव नहीं है। जिन देशों के पास आज परमाणु अस्त्र नहीं हैं वे भी शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए विस्फोट करके अनन्त परमाणु अस्त्र बनाने की क्षमता अर्जित कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने ब्रेझ्नेव के प्रस्ताव का यह वह बरम्बागत किया कि हमें आशा है कि बिना बहुत विलम्ब किए हुए हम परमाणु परीक्षणों पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाने में सफल होंगे जिससे पृथ्वी पर मे इम (परमाणु शक्ति) का खतरा निर्मूल किया जा सकेगा। वास्तव में केवल भाषण होते रहे-टोम रूप में कुछ भी नहीं किया गया।

1978 में संयुक्त राष्ट्र सघ का नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन

मार्च, 1978 में जेनेवा नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ जो तिसी ठोस परिणाम पर नहीं पहुँच सका। मई-जून, 1978 में संयुक्त राष्ट्र सभा के नि.शस्त्रीकरण अधिवेशन में महामन्त्रि डॉ. कुर्त वाल्दहीम ने प्रस्ताव रखा कि अस्त्रों पर रखे होने वाले प्रत्येक अरब डॉलर में से यदि 10 लाख डॉलर भी अन्तर्राष्ट्रीय नि.शस्त्रीकरण पर खर्च किए जाएँ तो ग्राम व्यक्ति का जीवन वही अधिक सुसहान हो सकता है। हम समय परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर 400 अरब डॉलर में अधिक खर्च होता है।

सम्मेलन में सोवियत विदेश मन्त्री आंद्रे गोमिको ने इस बान पर जोर दिया कि जब तक अस्त्रों की होड़ पर रोक नहीं लगती तब तक इस तरह का सम्मेलन

बेमानी है। सोवियत विदेशमन्त्री ने अपने भाषण में सुझाव प्रस्तुत किए—सभी तरह के परमाणु अस्त्रों के उत्पादन को समाप्त करना; सभी किस्म के विनाशकारी अस्त्रों पर प्रतिबन्ध और उनके उत्पादन को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाना, अधिक विनाशकारी परम्परागत हथियारों को त्यागने का आश्वासन। उन्होंने परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने की दिशा में भी निश्चित कदम उठाने का आह्वान किया।

चीन ने भी इस सम्मेलन की बहस में खुल कर भाग लिया। उसने पाँच नुक्ता कार्यक्रम प्रस्तुत किया—गैर परमाणु या परमाणुयुक्त देशों में विरुद्ध परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल न करने का आश्वासन; विदेशों से सभी सशस्त्र सेनाओं की वापसी, अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा परमाणु तथा परम्परागत अस्त्रों के निर्माण की होड़ समाप्त करना, किसी पड़ोसी देश की सीमा पर न तो सैनिक तैनात करना और न ही सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देना तथा किसी वहाने अन्य देशों पर आक्रमण करने से परहेज करना।

समुत्तराष्ट्र में गुटनिरपेक्ष देशों ने एक सात सदस्यीय सम्पर्क गुट की स्थापना की, ताकि परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने वाले देशों से निश्स्त्रीकरण करने की दिशा के कार्यक्रमों को लागू करने की हालत में अधिकतम रियायतें प्राप्त की जा सकें। ये देश हैं भारत, श्रीलंका, नाइजीरिया, मिस्र, युगोस्लाविया, अल्जीर और अर्जेंटीना।

भारत के प्रधानमंत्री श्री देसाई ने 9 जून के अपने भाषण में घोषणा की—“हमने अपने आप यह संकल्प लिया है कि हम परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे और न ही इन्हें वही से प्राप्त करेंगे।” श्री देसाई ने संयुक्त राष्ट्र सभा में निश्स्त्रीकरण के सम्बन्ध में एक चार सूत्री योजना भी प्रस्तुत की—

(क) एक घोषणा की जाए जिसमें अस्त्र-प्रौद्योगिकी में अनुसन्धानसहित परमाणु प्रौद्योगिकी के सैनिक कार्यों में प्रयोग को गैर-कानूनी घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) परमाणु अस्त्रों की गुणात्मक और परिमाणात्मक सीमा बाँध दी जाए और वर्तमान भण्डारों पर तुरन्त अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण रोक लगा दी जाए।

(ग) सभी परमाणु अस्त्रों को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हथियारों के भण्डारों को धीरे-धीरे खम करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाए जिसकी अवधि एक दशक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) एक व्यापक परीक्षण निषेध सन्धि की जाए जिसके अन्तर्गत इस सन्धि का उल्लंघन करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था होनी चाहिए जो मेरे विचार से केवल स्वतन्त्र निरीक्षण के द्वारा ही हो सकती है।

श्री देसाई ने कहा “यह प्रतिबन्ध वायुमण्डल में, भूमिगत, समुद्र में, और अन्तरिक्ष में किए जाने वाले परीक्षणों पर लागू होना चाहिए। सुरक्षात्मक उपायों

की व्यवस्था विश्वव्यापी और भेदभावहीनता पर आधारित होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निरीक्षण और सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था वास्तविक रूप में निष्पक्ष हो। यह राजनीति को लाए बिना लागू की जाए।”

कार्टर व ब्रेझ्नेव द्वारा साल्ट-2 पर हस्ताक्षर, जून 1979

1969 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच आरम्भ हुई सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता पिछले 10 वर्षों में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँची। 3 अक्तूबर, 1972 को समझौता-1 के प्रभावी होने के एक महीने बाद नवम्बर, 1972 में आरम्भ हुए समझौता-2 वार्ता का प्रोत्साहक परिणाम भी अभी निकल सभा जब 18 जून, 1979 को वियना में कार्टर एवं ब्रेझ्नेव ने साल्ट-2 (सामरिक आयुध परिसीमन की दूसरी सन्धि) पर हस्ताक्षर कर दिए। साल्ट-2 अथवा समझौता-2 को भी अस्त्र परिसीमन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं कहा जा सकता, तथापि यह आवश्यक है कि दोनों नेताओं ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। समझौता-2 में समझौता-1 की खाँियों को सुधारने का प्रयास किया गया। यह तय किया कि इस सन्धि के बाद अब दोनों देशों का सामरिक शस्त्र रखने का अधिकार सीमित हो जाएगा। दोनों देशों को केवल 2400 सामरिक प्रक्षेपास्त्र तथा भारी वमवर्षक विमान रखने का अधिकार होगा। सन् 1981 के बाद यह सख्या घटकर 2250 हो जाएगी। सामरिक शस्त्र रखने का अधिकार सीमित हो जाने के कारण सोवियत संघ को अपने सामरिक प्रक्षेपास्त्रों की सख्या में लगभग 250 की कटौती करनी पड़ेगी, जबकि अमेरिका अगर चाहे तो अभी 400 और प्रक्षेपास्त्र रख सकता है। दोनों देशों को एक नया सामरिक प्रक्षेपास्त्र बनाने का अधिकार भी होगा।

कार्टर तथा ब्रेझ्नेव दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि यह सन्धि काफी नहीं है। साल्ट-2 समझौते के कोई ठोस परिणाम दृष्टिगत नहीं हुए और समझौते के अनुपालन के सम्बन्ध में महाशक्तियाँ एक-दूसरे के प्रति सन्देहग्रस्त हैं। जून, 1980 में साल्ट-वार्ता में धीमी गति के लिए रूस ने पश्चिम को दोषी ठहराया और कुछ इसी प्रकार के प्रत्यारोप पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर भी लगाये जाने रहे हैं।

वर्ष 1980 तथा 1981 की घटनाएँ

वर्ष 1980, 1981 और 1982 का प्रथम चरण निःशस्त्रीकरण के प्रयासों की दृष्टि से निराशाजनक रहे और वास्तव में साल्ट-2 समझौते की एक प्रकार से धजियाँ ही उड़ गईं। वर्ष 1980 में निःशस्त्रीकरण-समझौतों के प्रति सन्देह और आग्नेय-प्रत्यारोप का आतावरण बना रहा। 20 जनवरी, 1981 को अमेरिका के चालीमवें राष्ट्रपति के रूप में रонаल्ड रीगन ने पद की शपथ ग्रहण की और कुछ समय बाद ही शस्त्रीकरण का एक नया दौर चल पड़ा। राष्ट्रपति रीगन ने सर्वप्रथम नाटो को शक्तिशाली बनाने और सोवियत संघ के एस एम 20, एम एम. 4 तथा एम एम. 5 प्रक्षेपास्त्रों का मुकाबला करने के लिए न्यूट्रान वम के निर्माण का

फैसला किया। इस विनाशकारी निर्णय से सारे विश्व का स्तब्ध रह जाना स्वाभाविक था। सोवियत संघ पर रीगन के इस निर्णय की बहुत तीखी प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था।

फरवरी, 1981 में सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस के समक्ष राष्ट्रपति ब्रेज्नेव ने अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर अपनी आठ सूची योजना प्रस्तुत की जिसके निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी सूत्र नं. 4, 5, 6, और 7 इस प्रकार थे—

(क) जहाँ तक सामरिक अस्त्र परिसीमन सन्धि (साल्ट) का प्रश्न है हम अविलम्ब अमेरिकी प्रसारण से वार्ता के लिए तैयार हैं। जिन क्षेत्रों में निश्चित परिणाम प्राप्त किये जा चुके हैं सोवियत संघ उसे वार्ता-पटल पर रखना चाहेगा।

(सूत्र नं. 4)

(ख) नई पनडुब्बियों के फैलाव को सीमित करने के लिए—अमेरिका की ओहियो किस्म की तथा कुछ वैसी ही सोवियत संघ की भी—हम समझौते के लिए तैयार हैं। हम वर्तमान प्रक्षेपास्त्रों के आधुनिकीकरण तथा नए विकास पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए भी सहमत हैं।

(सूत्र नं. 5)

(ग) हमारा सुझाव है कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक यूरोप में स्थापित मध्यम दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्र अस्त्रों का फैलाव रोक दिया जाए। प्रहार की दिशा में उन अस्त्रों को प्रभावहीन करने की हम में भी क्षमता है। हम उसका इस्तेमाल न करने का आश्वासन दिलाते हैं। इसके साथ ही अटलाण्टिक संगठन (नाटो) को अपनी गतिविधियों को सीमित करने का भी हमें आश्वासन दिलाना जाना चाहिए।

(सूत्र नं. 6)

(घ) लोगों को परमाणु युद्ध के मानवता पर विनाशकारी प्रभाव से अवगत कराया जाना चाहिए। हमारा सुझाव है कि इस कार्य के लिए एक सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय समिति गठित की जाए जो परमाणु के अन्वय से होने वाले प्रभाव का प्रदर्शन करे तथा उसकी अनुपयोगिता के बारे में लोगों की जानकारी प्रदान करे। इस समिति में विभिन्न देशों के विख्यात वैज्ञानिक शामिल किए जाएँ। इस समिति के निष्कर्षों में विश्व के सभी लोगों को अवगत कराया जाए।

(सूत्र नं. 7)

ब्रेज्नेव के प्रस्तावों का संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा अनेक राजनीतिक क्षेत्रों में स्वागत किया गया पर केवल प्रस्तावों और प्रति-प्रस्तावों को रखने से निःशस्त्रीकरण की समस्या सुलझने वाली नहीं है, इस दिशा में ठोस प्रयत्न होना आवश्यक है। दोनों महाशक्तियाँ और छोटे-मोटे अन्य राष्ट्र हथियारों की दौड़ में लगे हुए हैं और निःशस्त्रीकरण की वार्ताएँ कोई राजनीतिक चालें सिद्ध हो रही हैं। परमाणु अस्त्रों के विरोध में यूरोप में शान्ति मोर्चें खुले हैं लेकिन जनता का राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व पर इस दिशा में कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। यद्यपि सोवियत संघ भी शस्त्रीकरण अथवा हथियारों की दौड़ में पीछे नहीं है तथापि यह अवश्य कहना होगा कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन का सैनिक उन्माद

बहुत अधिक बड़ा-चड़ा है और वह अपने राष्ट्र को एक 'विराट शस्त्रीकरण' के मार्ग को चलाने को कटिबद्ध प्रतीत होते हैं। रीगन सोवियत इरादों के प्रति सशंकित और उनको शिकायत है कि सैनिक मामले वैसे ही अत्यन्त पेचोदा होते हैं तथा रूसी अपनी बिलम्बकारी चालों से उन्हें और भी अधिक उलझा देते हैं। रूसी लोग दिखावे के लिए 'शान्ति-अभियान' चलाते हैं जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। निःशस्त्रीकरण के सन्दर्भ में अथवा दूसरे शब्दों में महाशक्तियों के विराट् शस्त्रीकरण के सन्दर्भ में राष्ट्रपति रीगन ने नवम्बर, 1981 में अपना महत्त्वपूर्ण विदेशनीतिक भाषण दिया था जिससे इस विषय के अनेक पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है।

निःशस्त्रीकरण के सन्दर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन का विदेश-नीतिक भाषण (नवम्बर, 1981) और चार-सूत्री प्रस्ताव

अमेरिका के 'शस्त्रीकरण की नीति' के प्रति बढ़ते सन्देह के वातावरण को मिटाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने नवम्बर, 1981 में जो पहला महत्त्वपूर्ण विदेश-नीतिक भाषण दिया और उसमें तथ्यों को स्पष्ट करते हुए अस्त्र-नियन्त्रण की दिशा में उन्होंने जो चार-सूत्री प्रस्ताव रखा, वह निश्चित रूप से विचार योग्य है और कुछ 'लाभियों' में तो इसे 'मानवता के लिए विराट् कदम' की संज्ञा दी गई है। श्री रामनारायण यादव ने अमेरिकन राष्ट्रपति के प्रस्ताव और महाशक्तियों के विराट् शस्त्रीकरण पर अपने एक लेख में बड़ा स्पष्ट और प्रमत्त प्रकाश डाला है।¹

राष्ट्रपति रीगन ने अपने पहले महत्त्वपूर्ण विदेश-नीतिक भाषण के लिए समय बड़ी सावधानी से चुना था। 22 नवम्बर से शुरू होने वाली राष्ट्रपति और पार्टी प्रधान ब्रेज्नेव की बात यात्रा से ठीक 4 दिन और 30 नवम्बर, 1981 से जेनेवा में शुरू होने वाली नाभिकीय अस्त्र-नियन्त्रण वार्ताओं से दो सप्ताह पूर्व के सारी दुनिया को बसा देना चाहते थे कि परमाणुविक अस्त्रों की संख्या घटाने के लिए भी वे उत्तरे ही तत्पर हैं, जितने अपरिहार्य हो जाने पर उनकी संख्या और शक्ति बढ़ाने के लिए।

अमेरिका की 'शस्त्रीकरण की नीति' के प्रति यूरोप में बढ़ते हुए असन्तोष और शान्तिवाद प्रदर्शनों की बाढ़ के कारण अमेरिका ने इस भाषण के यूरोप में तरक्षण प्रसारण की व्यापक व्यवस्था कर रखी थी। टेलीवीजन के पर्दे पर राष्ट्रपति रीगन पहली बार अत्यन्त धीर-गम्भीर, तथ्यपरक और विश्वासजनक बने। उन्होंने जो कुछ कहा नवीनता थी। बम-से-बम पहली बार उन्होंने दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की घन्घाघुन्घ टोड को रोकने के लिए ऐसा प्रस्ताव रखा, जिसे यदि मूर्त रूप दिया जा सके तो दुनिया को बड़ी राहत मिलेगी। उनके इस चार-सूत्री प्रस्ताव

1 रामनारायण यादव : 'रक्त-अमेरिका मानवता के लिए विराट् कदम'
(दिनमान, दिसम्बर 1981, पृष्ठ 37-38)

में सिद्धान्ततः वे सारी बातें शामिल हैं, जिन पर पश्चिमी जर्मनी सहित 'नैटो' के सभी प्रमुख देशों की मांगों पर बल दिया जाता रहा है।

जैसा कि राष्ट्रपति रीगन ने स्वयं भी कहा, 30 नवम्बर से जेनेवा में शुरू होने वाली अस्त्र-नियन्त्रण वार्ताओं को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने सोवियत नेता ले भिनेव को एक पत्र में निम्नलिखित चार-सूत्री प्रस्ताव पेश किया है—

1. यदि सोवियत संघ अपने एस. एस. 20, एस. एस. 5 प्रक्षेपास्त्रों (रॉकेटों) को विखण्डित कर दे, तो अमेरिका भी अपने पेशिंग-2 तथा भूमि आधारित अन्य प्रक्षेपास्त्रों की तैनातगी को रद्द करने के लिए तैयार है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के तथाकथित 'शून्य विकल्प' की भी ठीक यही माँग है।

2 अमेरिका अगले वर्ष यथासम्भव शीघ्र ही 'सामरिक अस्त्रों को घटाने के बारे में वार्ताएँ' शुरू करने का प्रस्ताव रखता है क्योंकि उद्देश्य सामरिक (महाविनाशक परमाणुविक) अस्त्रों की संख्या में भारी कटौती करना होगा, इसलिए इन वार्ताओं को, 'सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ताएँ' (साल्ट) न कह कर 'सामरिक अस्त्र परिपटन वार्ताएँ' (स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टाक्सस्टार्ट) कहा जाएगा।

3. यूरोप में पारम्परिक (अनातिवीर्य) शस्त्रास्त्रों के मामले में भी एक निचले स्तर पर बराबरी लाई जानी चाहिए।

4. शान्ति बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि अनिश्चय या गलत वार्ताओं के कारण अचानक आक्रमण एवं युद्ध की सम्भावना को भी कम किया जाए।

रूस ने यद्यपि इस प्रस्ताव को 'प्रचारवादी हथकण्डा' बता कर तुरन्त ठुकरा दिया है, पर अपनी 'ईमानदारी' सिद्ध करने में उसे भी भारी कठिनाई हो रही है। स्वयं फ्रांस की समाजवादी सरकार भी, नौ 'नैटो' की सैनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती, राष्ट्रपति रीगन के बताए इन तथ्यों को सही मानती है कि तनाव संश्लिष के मुलावे में आकर अमेरिका और पश्चिमी देश पिछले एक दशक से अपनी सेना का आकार और सैनिक व्यय घटाते रहे हैं, जबकि रूस चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा रहा। उसका सैनिक व्यय एक तिहाई बढ़ गया है और सैन्यबल अमेरिका से दुगुना हो गया है। राष्ट्रपति रीगन के अनुसार आज रूस के पास 50 हजार टैंक हैं, जबकि अमेरिका के पास केवल 11 हजार। पिछले वर्षों में पश्चिम यूरोपीय 'नैटो' देशों से अमेरिका ने एक हजार परमाणुविक आयुध शीपों (बमों) वाले अपने सभी मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हटा लिए जबकि रूस ने अकेले 'एस एस 20' प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से ही पश्चिम यूरोप पर लक्ष्य करते हुए 750 नए आयुध शीपों (वारहेड्स) लगाए। मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों पर लगे रूसी आयुध शीपों की कुल संख्या 1100 हो गई है। राष्ट्रपति रीगन का कहना है कि 'नैटो' के पास रूस की इस तैयारी का फिलहाल कोई उत्तर नहीं है, इसीलिए 1983 से पश्चिम यूरोप में मध्यम दूरी तक मार करने वाले 'पेशिंग-2' और 'क्रूज मिसाइल' तैनात करने की बात थी। अमेरिका इन प्रक्षेपास्त्रों की यूरोप में तैनातगी का इरादा त्याग देगा यदि पहले रूस अपने बड़े हुए कदम पीछे हटा ले।

रूस अपने 'एस एस-20' राकेटों को यूराल पर्वतों से पीछे, यानी यूरोपीय रूस से हटा कर एशियायी हिस्से में ले जाने को तैयार है, किन्तु 'नटो' देश इसे घाँव में धूल भोकरना मानते हैं, क्योंकि 5 हजार किलो मीटर तक प्रहार कर सकने वाले ये प्रक्षेपास्त्र यूराल के पीछे से भी रोम से लेकर लन्दन और एम्सटर्डम तक हर ठिकाने पर अचूक मार कर सकते हैं। यह नहीं, चलते-फिरते प्रक्षेपण वाहनों पर लगा हॉन के कारण रूसी उन्हें किसी भी समय चुपके से यूराल के इसे अपने यूरोपीय हिस्से से भी पुनः ला सकते हैं। एक तर्क यह भी है कि हो सकता है रूस उन्हें जापान पर लक्षित कर दे अतः अमेरिका और उसके मित्र देशों की माँग है कि पहले रूस इन प्रक्षेपास्त्रों को पूरी तरह नष्ट कर दे, तभी बात बन सकती है।

रूस की ओर तत्काल जो अनीपचारिक प्रतिक्रिया सुनने में आई है, उसके अनुसार रूस राष्ट्रपति रीगन के 'शून्य विकल्प' को कोई विकल्प मानता ही नहीं। उसका कहना है कि हम से तो आशा की जाती है कि हम अपने सभी मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट कर दें, जबकि अमेरिका अपनी पनडुब्बियों में लगे इसी तरह के प्रक्षेपास्त्रों को बहस से बाहर रखना चाहता है। वास्तव में स्थिति यह है कि अमेरिका ने रूसी आणविक पनडुब्बियों में लगे प्रक्षेपास्त्रों, और अपने 'फारवर्ड बेस्ड सिस्टम' (एफ बी एस) वाले विमानों की तरह रूसी 'बैकफायर' बमवर्षकों को भी फिलहाल अलग ही रखा है। वैसे भी, वार्ताएँ शुरू होने के पहले किसी प्रस्ताव से यह आशा की ही कैसे जा सकती है कि उसमें वह सब कुछ शामिल हो, जो वार्ताओं के नतीजे के तौर पर अन्त में सामने आना चाहिए। बातचीत के दौरान भी तो लेन-देन और फेर-बदल होती रहती है।

परमाणु अस्त्रों को नियन्त्रित करने के बारे में 30 नवम्बर, 1981 से जेनेवा में दोनो महाशक्तियों के बीच वार्ताओं का जो नया क्रम किसी तरह शुरू हुआ वह पहले दौर के बाद स्थगित कर दिया गया। पहले दौर में दोनो पक्ष मध्यम दूरी तक मार कर सकने वाले एक-दूसरे के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों—अर्थात् परमाणु बमबाही राकेटों—की यूरोपीय भूमि पर संख्या घटाने के बारे में बातें करनी थीं, लेकिन केवल अगली बैठक का स्थान और समय तय करने के प्रयास के बाद पहली बैठक समाप्त हुई। दूसरे दौर में अन्तर महाद्वीपीय-यानी सामरिक-प्रस्त्रों की संख्या सीमित या कम करने के बारे में 'साल्ट' वार्ताओं के क्रम को पुनः शुरू करने का प्रयास किए जाने की बात है। यह दूसरा और सम्भवतः मार्च, 1982 में जेनेवा में ही शुरू होगा। अमेरिका 'मखिल यूरोपीय निःशस्त्रीकरण सम्मेलन' के नाम से एक तीमरे बहुपक्षीय दौर के लिए भी प्रयत्नशील है, किन्तु उसके प्रयत्नों की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि स्पेन की राजधानी माद्रिद में यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग के हेलसिंकी सम्मेलन की समीक्षा करने के लिए पिछले एक वर्ष से जो विराट् सम्मेलन चल रहा है, उसका कोई ठोस परिणाम भी निश्चलता है या नहीं। हमी गुट की अमेरिका और टालमटोल नीतियों के कारण यह सम्मेलन 15 देशों का एक मासूहिक जुगाली आयोजन बन कर रह गया है।

निःशस्त्रीकरण की दिशा में ये प्रस्तावित बैठकें पूर्व और पश्चिम के बीच न तो पहली बैठकें होंगी और न ही अन्तिम। इनके पहले 'साइट-1' और 'साइट-2' नामक दो सम्मेलन भी हो चुके हैं जिनके बारे में वार्ताएँ 1968 से ही चलती रही हैं। इन सम्मेलनों में रूस और अमेरिका ने दो-वर्षीय आधार पर अपने महाविनाशक सामरिक अस्त्रों की संख्या परिसीमित करने के वायदे किए थे।

नाभिकीय अस्त्रों पर लागूपेट लगाने की वार्ताओं के धरावा 1973 से हो आस्ट्रिया की राजधानी वीएना में 'नैटो' गुट के 12 और 'वारसा' गुट के 6 देश पारस्परिक आधार पर मेनाओं में मन्तुलित कटौती करने के बारे में बातें करते रहे हैं। यह अलग बात है कि 8 साल तक बोलने-बनियाने के बाद भी दोनों गुट यह नहीं जानते कि किम के पास कितने सैनिक हैं और कितनी कटौती 'सन्तुलित' कहलाएगी।

अमेरिका की शिकायत है कि सैनिक मामले बैसे ही अत्यन्त पेचीदा और जटिल होते हैं, रूसी अपनी विलम्बकारी चालों से उन्हें और भी उलझा देते हैं। दुनिया को भ्रम में रखने के लिए वे एक के बाद एक 'शान्ति-प्रभियान' छेड़ेंगे, अपने को शान्ति का सबसे बड़ा प्रहरी बतायेंगे, पर वार्ता की मेज पर ऐसे हर सम्मेलन को मानने से आनाकानी करेंगे, जिसमें घोलाधड़ी और दुरुपयोग के निदान के लिए मौके पर जाकर जाँच करने का प्रावधान होगा। अमेरिका अपने सैनिक प्रतिष्ठानों की रूसियों द्वारा जाँच कराने के लिए तैयार है, पर रूसी अपने यहाँ किसी की नहीं आने देना चाहते। 'यह हाल तब है', एक अमेरिकी राजनयिक ने एक बार कहा, 'जब लेनिन ने स्वयं कहा था—विश्वास करना अच्छा है, पर नियन्त्रण और भी बेहतर है।' यह देख लेने के बाद कि तनाव ग्रंथित्य की माला जपते-जपते सोवियत सैनिक शक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, अमेरिका यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बिना पर्याप्त जाँच-व्यवस्था के रूस किसी सैनिक सम्मेलन का ईमानदारी से पालन करेगा। एक तटस्थ देश स्वीडन की जल सीमा में प्राणविक शस्त्रों से लैस पनटुन्बी भेज कर रूस ने दूसरों का विश्वास भी खो दिया है।

जहाँ तक रूस की विलम्बकारी चालों का प्रश्न है, 1973 से वीएना में चल रही 'सैन्य बल में परस्पर सन्तुलित कटौती' के बारे में वार्ताएँ इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं। 250 से अधिक बैठकों के बाद इस साल 25 सितम्बर को इन वार्ताओं का 25वाँ दौर शुरू हुआ, पर रूसी भव भी टस-से-मस होने का नाम नहीं ले रहे। वे यह मानने को तैयार ही नहीं कि 'वारसा' गुट के पास 'नैटो' गुट की अपेक्षा मध्य यूरोप में पौने दो लाख सैनिक अधिक हैं। न तो वे 'वारसा' गुट की कुल सैनिक सख्या ही बताने के लिए तैयार हैं, न ही पश्चिम को भूठा साबित करने के लिए उसे अपने यहाँ प्राकर स्वयं वस्तुस्थिति देखने की अनुमति ही देते हैं। 8 सालों से 19 देशों के राजनयिक हर गुरुवार को वीएना के 'नोये होफबुर्ग' महल में एक विशाल गोलाकार मेज के चारों ओर आधे घण्टे के लिए मिलते हैं, हर बार बीच से एक नए राजदूत का भाषण सुनते हैं और सलाह-मुामा करते हुए अगले

गुम्बार तक के लिए बँटक स्थगित कर देते हैं। रूस सैनिक संख्या को एक नाजुर्ग मुद्रा मामला बता कर कोई जानकारी देने या दूसरे की जानकारी मानने के लिए तैयार ही नहीं होता।

यही हाल हेलोसिकी सम्मेलन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नवम्बर, 1980 में माद्रौद में चल रहे सम्मेलन का भी है, जहाँ अखिल यूरोपीय निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के आयोजन के समय एव स्थान के बारे में निर्णय लिया जाना है। यहाँ रूस के मुख्य वार्ताकार हैं नियोनिद इत्यीचेव जो चीन के साथ 12 वर्षों तक सीमा-विवाद पर बिना परिणाम वार्ताएँ करने के लिए नाम बमा चुके हैं। यह सम्मेलन इस वर्ष अप्रैल में ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन तब तक उसकी कोई कार्यसूची ही नहीं तय हो पाई थी। उस समय श्री इत्यीचेव ने कहा था कि यदि जरूरी हुआ तो वे 'हमेशा के लिए' वहीं पड़े रहेंगे।

अमेरिकी मुनो का कहना है कि निःशस्त्रीकरण के बारे में रूस के साथ हर बातचीत केवल इस मुद्दे पर आकर टूट जाती है कि वह किसी भी सम्मेलन में मौके पर जाकर जाँच की बात स्वीकार नहीं करता। उसका तर्क है कि हर पक्ष को दूसरे पक्ष की जाँच के लिए 'अपने राष्ट्रीय तकनीकी साधनों' पर ही भरोसा करना चाहिए। तात्पर्य जामूमी उपग्रहों और सैनिक उड़ानों की टोह लेने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है। लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञ केवल दूर से टोह लेने को ही पर्याप्त नहीं मानते। उनका कहना है कि इससे यह नहीं पता चल सकता कि किसी नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र पर केवल एक ही आयुध शीर्ष (बम) लगा हुआ है या कई शीर्ष हैं। भावी विनाश की मात्रा प्रक्षेपास्त्रों (राकेटों) की संख्या पर नहीं, इन आयुध शीर्षों की संख्या पर ही निर्भर करती है। मास्को को एक सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि पश्चिमी देशों के स्वतन्त्र प्रेम के कारण उनकी सामरिक शक्ति के बारे में लगभग सारी जानकारी उसे घर बैठे ही मिल जाती है।

अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मन्त्री हेनरी कीमिंगर ने तो यहाँ तक लिखा है कि "सामरिक अस्त्र पश्चिमीयन वार्ताओं (माल्ट) के समय कई बार मोरियन वार्ताकारों को अपने देश की सामरिक क्षमता के बारे में पहली जानकारी अमेरिका के वार्ताकारों से मिली। 'माल्ट' वार्ता के समय अमेरिकी पक्ष ने रूसियों को अमेरिकी एव ज्ञान रूसी प्रक्षेपास्त्र-विरोधी प्रक्षेपास्त्रों ए बी एम के बारे में एक सूची प्रदान की। नॉन माल वाद रूसियों ने बिना पूछे बनाए वामचात्ता पर एव नए ए बी एम रेंज का परीक्षण शुरू किया। अमेरिका के प्रतिवाद करने पर उन्होंने कहा कि यह रेंज तो हमेशा ही कार्यरत रही है। जब अमेरिकियों ने उन्हें वार्ता के समय की सूची दिखाने हुए कहा कि इसमें तो दस रेंज का नाम नहीं है, तो रूसियों ने उस सूची को सही मानने में इन्कार कर दिया। वह यह भी बनाने के लिए तैयार नहीं हुए कि वामचात्ता में हो क्या रहा है।"

निःशस्त्रीकरण की समस्याएँ

(Problems of Disarmament)

निःशस्त्रीकरण के इतिहास में यह ज्ञान होता है कि इनमें बहुत थोड़े प्रयास

ही सफल हो सके थे, अधिकांश को असफलता का मुँह देखना पड़ा। इस निरन्तर असफलता के पीछे अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जो किसी भी समझौतों को सर्वमान्य नहीं बनने देती। मॉर्गेंथौ (Morgenthau) ने निःशस्त्रीकरण की चार समस्याओं का बर्णन किया है। वे निम्न प्रकार हैं—

- (1) विभिन्न राष्ट्रों के शस्त्रों के बीच अनुपात (Ratio) कितना रहेगा ?
- (2) वह मापदण्ड क्या है जिसके अनुसार इस अनुपात के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार एवं गुणों के अस्त्र विभिन्न देशों के लिए निर्धारित किए जाएँगे ?
- (3) उक्त दो प्रश्नों के उत्तरों का हथियारों की सोचो गई कमी पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा ?
- (4) निःशस्त्रीकरण का अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

मॉर्गेंथौ का कहना है कि निःशस्त्रीकरण के किसी भी प्रयास की सफलता का मूल्यांकन इन चार प्रश्नों के सम्बन्ध में होना चाहिए। इन प्रश्नों के जैसे उत्तर प्राप्त होंगे उनसे यह जाना जा सकेगा कि उनमें सफलता एवं असफलता की मात्रा कितनी-कितनी थी।

निःशस्त्रीकरण के मार्ग में कठिनाइयाँ (Difficulties in the Way of Disarmament)

1. महाशक्तियाँ अपने शस्त्रास्त्रों के आधुनिकीकरण का मोह छोड़ने को तैयार नहीं हैं; अतः स्वाभाविक है कि देश के आधुनिकतम आयुधों के जवाब में दूसरा देश उससे भी बड़कर आयुध बनाने की सोचता है और इस तरह जो भी निःशस्त्रीकरण-समझौते होते हैं वे बहुत ही आंशिक और व्यवहार में प्रभाव-शून्य होते हैं। उदाहरणार्थ, जून-जुलाई, 1974 के जिलर-सम्मेलन में रूस और अमेरिका के बीच प्रभावी सामरिक अस्त्र-परिसीमन-समझौता न हो पाने के राजनीतिक क्षेत्रों में दो प्रमुख कारण बताए गए हैं—(क) हाल में अमेरिका के लक्ष्य भेदकर स्तनः लोट जाने वाले एम. आई आर. की प्रक्षेपास्त्रों के बारे में यह तथ्य सामने आया है कि प्रथम आक्रमण की स्थिति में ये प्रक्षेपास्त्र शत्रु के ठिकानों को उतनी क्षति नहीं पहुँचा पाएँगे जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उनके आपस में टकराकर नष्ट हो जाने की अधिक सम्भावना है। प्रेरणों का मत है कि इस लोच के बाद अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग अधिक बड़े और ठिकाने पर सही मार करने वाले अस्त्रों के निर्माण के लिए सरकार पर दबाव डालेगा। हो सकता है कि इस स्थिति के कारण निम्न ने सामरिक अस्त्र परिसीमन जैसा समझौता टालने का भी प्रयास किया हो। (ख) दूसरे कारण का सम्बन्ध सोवियत संघ से था। यह तो सन् 1972 के समझौते के समय ही स्पष्ट हो गया था कि जब तक दोनों महाशक्तियाँ आतमण और प्रतिरक्षा, दोनों ही दृष्टियों में परमाणु-अस्त्रों के मामले में समान स्तर पर

नहीं पहुँच जाती, तब तक उनके बीच सामरिक-अस्त्र-परिसीमन के बारे में पूर्ण समझौता नहीं हो सकेगा। आशा थी कि सोवियत सघ शीघ्र ही प्रक्षेपास्त्रों के बारे में अमेरिका के बराबर न सही, उसके निकट तो पहुँच ही जाएगा; किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इस क्षेत्र में अभी वह अमेरिका से पीछे है—न केवल इसलिए कि उसके विश्व भर में सैनिक अड्डे न होने के कारण वह अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता है, बल्कि इसलिए भी कि उसके पास अमेरिका से कम परमाणु शस्त्र हैं।

इन परिस्थितियों में सामरिक अस्त्र-परिसीमन के बारे में किसी व्यापक समझौते की अपेक्षा कैसे की जा सकती है ?

2. कूटनीतिक और सैनिक क्षेत्रों में अमेरिका की परमाणु-शक्ति सोवियत सघ से बहुत अधिक कूती जाती है और प्रक्षेपास्त्रों के बारे में लगभग तीन गुनी अधिक। फिर भी वह नए परमाणु-प्रक्षेपास्त्रों को बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है और अपने प्रयत्नों का औचित्य सिद्ध करने के लिए वह समय-समय पर सोवियत सघ की परमाणु शक्ति को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत करता रहा है। सन् 1960 में अपने चुनस्य-अभियान में जॉन एक कॅनेडी ने यही किया। उसके बाद अमेरिका ने जब एम आई. आर. वी. प्रक्षेपास्त्र-प्रणाली पर काम शुरू किया, तब भी यह कहा गया कि सोवियत सघ ने तालीन और गालोश नामक प्रतिरक्षात्मक प्रक्षेपास्त्र-प्रणालियों का विकास कर लिया है, अतः अमेरिका के लिए एम आई आर. वी. प्रणाली अनिवार्य हो गई है। लेकिन जब एम आई आर. वी. प्रणाली पर जोरों से काम होने लगा तो अमेरिका ने यह स्वीकार किया कि सोवियत सघ की उक्त प्रतिरक्षा व्यवस्था से उसे कोई खतरा नहीं है। फिर भी प्रक्षेपास्त्र निर्माण के व्यापक कार्यक्रम का औचित्य सिद्ध करने के लिए अगले कुछ वर्षों में या सन् 1981 के बाद सोवियत सघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली परमाणु क्षमता का तर्क दिया जा रहा है। यह एक ऐसा बहाना है जिसके रहते अस्त्र-दौड़ रोकने की बात नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें न तो अमेरिका के ब्रिडेंट पनडुब्बियाँ और बी-1 बमवर्क बनाने के कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही प्रतिरक्षा-व्यवस्था को उत्तरोत्तर मुदृढ़ करने का सोवियत सघ का कार्यक्रम प्रभावित होगा। यह स्थिति सामरिक अस्त्र परिसीमन-समझौते की सम्भावनाओं के प्रतिकूल है।

3. अणु-शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों का निर्धारण अनेक भ्रान्तिक एवं बाह्य तत्त्वों से प्रभावित होता है। एक देश पहले अपने राष्ट्रीय हितों की ओर दृष्टि डालता है तथा बाद में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व हित को देखता है। इसी आधार पर फ्रांस ने परीक्षण-प्रतिरोध-गन्धि का समर्थन नहीं किया। दो या अधिक राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध आज इतने अस्थिर हैं कि वन का मित्र आज का दुश्मन बन जाता है। इन परिस्थितियों में अणु-आयुधों के रहने से आतंकपूर्णकारी पर प्रतिबन्ध लग जाता है और वह तुरन्त युद्ध छेड़ने का साहस नहीं कर पाता क्योंकि दूसरे देश की शक्ति उमका भी विनाश कर सकती है। अस्थिर सम्बन्धों का भय तथा हठाने निहित खतरे और लाभ की भावनाएँ शस्त्रों को सीमित करने के मार्ग में बाधक

बन जाती हैं। आजकल मैनिंक तकनीकी का इतना विकास हो चुका है कि निःशस्त्रीकरण का नाम लेकर किसी को भी धोता दिया जा सकता है। शक्तिशाली शस्त्रों को छुटाकर ऊपरी सेना घटाकर निःशस्त्रीकरण का दिखावा किया जा सकता है। जब तक यह भय दोनों पक्षों के मन में रहेगा तब तक निःशस्त्रीकरण का भविष्य उज्ज्वल नहीं है।

4. राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता की भावना के कारण एक देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसकी निःशस्त्रीकरण की क्षामान्विति की जाँच के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय सस्या बनाई जाए। इम प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतन्त्रता पर जो अकुश लगता है उसे मानने को कोई तैयार नहीं होता। यही कारण है कि निःशस्त्रीकरण योजना की सफलता में पूर्ण विश्व-सरकार की स्थापना का समर्थन किया जाता है।

5. निःशस्त्रीकरण के कारण एक देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। शस्त्रों के निर्माण पर व्यय होने वाली भारी राजि का शस्त्र-निर्माण बन्द कर देने पर रचनात्मक कार्यों में कैसे उपयोग किया जाएगा, उससे अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त होने से कैसे बचाया जाएगा आदि भागंकाएँ उठनी हैं तथा यह भाशा भी रहनी है कि इसे अर्द्ध-विकसित देशों के विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकना है। यह भी सम्भव है कि निःशस्त्रीकरण के आर्थिक परिणामों का मय एवं भाशा अवास्तविक है। इस भाशा एवं भय का पश्चिम के सम्पन्न समाज पर क्या असर होना है, यह भी अनुमान का विषय है।

6. निःशस्त्रीकरण करते समय देशों के शस्त्रों का जो अनुपात निर्धारित किया जाना है उसके कारण देशों के बीच मन-मुटाव व अविश्वास की भावना पैदा होनी है। शस्त्रों की सीमा-निर्धारण के समय प्रत्येक देश को दूसरे देश के प्रति यह शका रहती है कि शायद वह अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा विरोधी पक्ष की शक्ति घटाने का प्रयत्न कर रहा है। तकनीकी रूप से यह बड़ा कठिन नाम है कि एक देश की सैनिक आवश्यकता को ज्ञात किया जाए तथा उसी अनुपात में उसकी सैनिक शक्ति को घटाया जाए। जॉन फॉस्टर डलेम के मतानुसार इनी समस्या के कारण अमेरिका द्वारा निःशस्त्रीकरण की योजनाओं का समर्थन सच्चे दिल से नहीं किया जा सका। इन समस्या के समाधान के लिए दो सुभाव प्रस्तुत किए जाने हैं—
(i) पूर्ण रूप से निःशस्त्रीकरण कर दिया जाए (ii) अन्तर्राष्ट्रीय पुनिम-शक्ति द्वारा देशों को सामूहिक सुरक्षा की गारन्टी दी जाए। किन्तु ये सुभाव भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक पहले शस्त्रों को कम न किया जाए, इसलिए अनुपात की समस्या मूल है।

7. यह कहा जाता है कि अविश्वासपूर्ण वातावरण में निःशस्त्रीकरण और शस्त्रों का नियन्त्रण तथा अन्य राजनीतिक समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। यदि देशों में पारस्परिक विश्वास रहे तो शस्त्रों की आवश्यकता ही न रहे और निःशस्त्रीकरण की समस्या भी पैदा न हो। पूर्ण अविश्वास की स्थिति अराजकता

एवं पूर्ण तानाशाही में से एक को स्थापित कर देगी। यह आशा की जाती है कि नि.शस्त्रीकरण की समस्या के सुलभने के बाद दोनों गुटों में विश्वास की भावना आ सकती है। अविश्वास के कारण कोई समझौता नहीं हो पाता; होता भी है तो सच्चे रूप से श्रियान्वित नहीं हो पाता।

8 एक समस्या यह सामने आती है कि पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाए या नि.शस्त्रीकरण किया जाए। ये दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा डालते हैं और एक के हल हो जाने पर दूसरे का हल हो जाना सुगम है। यह सोचा जाता है कि शस्त्र भण्डों का कारण है और इनको घटाने में अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम और मैत्री बढ़ेगी। किन्तु यह प्रयास एकपक्षीय होगा। होना यह चाहिए कि मनमुटाव, अविश्वास एवं प्रतिद्वन्द्विता को दूर करने के लिए हर दिशा में प्रयास किया जाए। मडरियागा के शब्दों में, "शस्त्रीकरण की समस्या का समाधान इस समस्या में ही नहीं खोजा जा सकता, किन्तु इसके बाहर ही खोजा जा सकता है।" असल में नि.शस्त्रीकरण की समस्या नि.शस्त्रीकरण की समस्या नहीं है, यह वास्तव में विश्व-समुदाय के संगठन की समस्या है।

वास्तव में नि.शस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक महाशक्तियों में मौलिक मतभेद बने रहेंगे। नि.शस्त्रीकरण में वांछित सफलता न मिलने का एक कारण यह भी है कि 'आणविक क्लब' (The Nuclear Club) की सदस्यता बड़ी सीमित है। अभी तक अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ही आणविक शस्त्रास्त्रों के क्षेत्र में खिलाड़ी हैं, लेकिन जब विश्व के अन्य देश भी मैदान में उतर आएंगे और जरा-सी टकराहट पर अणु-युद्ध का खतरा मजीब हो उठेगा तो महाशक्तियाँ सम्भवतः बाध्य हो जाएँगी कि वे नि.शस्त्रीकरण (विशेषकर अणु-शस्त्रों के क्षेत्र में) की दिशा में गम्भीर प्रयास करें। अभी तक इस ओर जो भी कदम उठाए गए हैं अथवा समय-समय पर जो सन्धियाँ की गई हैं वे प्रदर्शनात्मक और प्रचारात्मक ही अधिक हैं, अन्यथा महाशक्तियों का यह पुरजोर प्रयास जारी है कि अभिनव सामरिक अणु-शस्त्रों की खोज की जाए और वर्तमान शस्त्रों की विनाशक शक्ति बढ़ाई जाए।

क्या नि.शस्त्रीकरण का अर्थ शान्ति है ?

प्रायः प्रश्न किया जाता है—क्या नि.शस्त्रीकरण का अर्थ शान्ति है ? वास्तव में "बार-बार नि.शस्त्रीकरण का अर्थ शस्त्रों में कटौती की अपेक्षा वृद्धि रहा है।" नि.शस्त्रीकरण का आधुनिक दर्शन इस कल्पना को लेकर चलता है कि आदमी लड़ने है, क्योंकि उनके पास हथियार हैं। इस धारणा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी सब हथियार त्याग दें तो सब प्रकार के युद्ध अगम्य हो जाएँगे। इसी आधार पर कहा जाता है कि नि.शस्त्रीकरण-नार्चक्रम का उद्देश्य युद्ध रोकना होना चाहिए, न कि युद्ध में प्रयोग होने वाले शस्त्रों को नियन्त्रित करना। परन्तु नि.शस्त्रीकरण के बकीर इसमें विपरीत दिशा में सोचते हैं। उनका कहना है कि आदमी इसलिए नहीं लड़ने कि उनके पास हथियार हैं। वे हथियार रखते हैं, क्योंकि वे लड़ना आवश्यक समझते हैं। उनमें हथियार ले लिए जायें तो

या तो वे केवल धूम से लड़ेंगे या लड़ने के लिए नवीन हथियार प्राप्त करेंगे। जो वस्तु युद्ध करती है वह है मानव-हृदय की अवस्था जिसमें युद्ध दो अवस्थाओं से न्यून प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में बीनारी का पता लग सकता है जिसका शस्त्रों की इच्छा करना और उनको प्राप्त करना केवल लक्षण है। जब तक मनुष्य एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करना और एक दूसरे की सम्पत्ति को छीनना चाहते हैं और जब तक वे एक दूसरे से डरते और घृणा करते हैं, तब तक वे अपनी इच्छाओं को सन्तुष्ट करने और अपनी भावनाओं को शान्त करने का यत्न करेंगे। जहाँ ऐसी शक्ति विद्यमान हो कि वह इन इच्छाओं और भावों की अभिव्यक्तियों को अहिंसक दिशाओं की ओर मोड़ दे, वहाँ मनुष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अहिंसक साधनों की खोज करे।

निःशस्त्रीकरण और शान्ति की समस्या पर विचार करते हुए माँगेन्थो ने लिखा है कि—“अन्तर्राष्ट्रीय भगडों के सामान्य निबटारे में निःशस्त्रीकरण में कम से कम शस्त्रों का नियमन एक अनिवार्य कदम है, तो भी यह पहला कदम नहीं हो सकता। शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता शक्ति-प्रतियोगिता का प्रतीक भी है और साधन भी। तब तक राष्ट्र शक्ति-द्वन्द्व में प्रतिकूल माँगे वरेंगे। शक्ति-समर्पण का परस्पर सन्तोषजनक निबटारा निःशस्त्रीकरण की पूर्ण शर्त है। एक बार सम्बन्धित राष्ट्रों के शक्ति-विभाजन पर परस्पर सन्तोषजनक समझौता हो जाए, तो वे अपने शस्त्रों को घटाने और सीमित करने के योग्य हो सकते हैं। अपनी ओर से निःशस्त्रीकरण का परिशीलन शान्ति-स्थापना के प्रति अधिक योगदान होगा। राष्ट्र उस माना में निःशस्त्रीकरण के विषय का निबटारा कर सकेंगे जिस मात्रा में वे राजनीतिक समझौता कर पाएँगे।”

शस्त्रीकरण-प्रतियोगिता से किसी तरह कम न होते हुए, शस्त्रीकरण सम्बन्धित-राष्ट्रों में शक्ति-सम्बन्धों का प्रतीक है। शस्त्रीकरण-प्रतियोगिता से कम न होकर निःशस्त्रीकरण की उन शक्ति-सम्बन्धों पर प्रतिक्रिया होती है जिनसे यह पैदा हुआ जैसे भय, जिसे यह उत्पन्न करती है और भय, जिसे यह लावती है। शस्त्रीकरण-प्रतियोगिता शक्ति-समर्पण को जटिल बनाती है। वैसे राजनीतिक खिचाव को कम कर और सम्बन्धित राष्ट्रों के उद्देश्यों में विश्वास उत्पन्न कर निःशस्त्रीकरण का राजनीतिक स्थिति के सुधारने में योगदान है। निःशस्त्रीकरण का यह योगदान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कायम रखने में हो सकता है। यह महत्वपूर्ण योगदान है, परन्तु स्पष्ट रूप में यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शान्ति की समस्या का हल नहीं है।

हथियारों के प्रसार का निवसन-सिद्धान्त

निःशस्त्रीकरण के प्रयास दिखावटी अधिक हैं, व्यावहारिक कम। विश्व में शस्त्रास्त्रों का भण्डार बढ़ता जा रहा है और महाशक्तियाँ शस्त्रास्त्रों के विक्रय में होड़ कर रही हैं। हथियारों के प्रसार में अमेरिका के ‘निवसन-सिद्धान्त’ का विशेष

योगदान रहा है। निक्सन को वाटरगेट काण्ड से डूबा, लेकिन निक्सन-सिद्धान्त जीवित है, जिस पर चलकर अमेरिका हथियारों के प्रसार में लगा हुआ है।

अमेरिका ने हथियारों के प्रसार में नई तकनीक अपनाई है। उसने बड़े हथियारों के स्थान पर छोटे हथियारों के फैलाव पर जोर देना शुरू किया है। जहाँ कहीं सम्भव होता है इन छोटे हथियारों के कारखानों को भी स्थापित किया जाता है ताकि अमेरिका का उस देश में हस्तक्षेप कायम रहे। ये छोटे हथियार दक्षिण-पूर्वशिया, लातीनी अमेरिका और यूरोप के कई देशों को दिए गए। अमेरिका ने इन देशों को इनकी तकनीकी और प्राविधिक जानकारी भी दी। इन छोटे हथियारों के प्रसार की शुरुआत अमेरिका ने वियतनाम से की। दक्षिण-वियतनाम में उसने बड़े पैमाने पर ये हथियार बेचे। जब लडाई की गति में ढील आने का खतरा पैदा हुआ, तो अमेरिका ने संगीन में इन हथियारों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। इसे 'निक्सन-सिद्धान्त' कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि धीरे-धीरे स्थानीय सेना अमेरिकी सेना का स्थान ले लेगी और उनकी रक्षा का भार अमेरिकी सैनिक के स्थान पर हथियारों की यह बहुलता ग्रहण कर लेगी। इसका मतलब यह हुआ कि लडाई में सीधा हिस्सा न लेकर अप्रत्यक्ष तौर से अमेरिका फिर भी अपने समर्थकों की मदद करता रहेगा। इसी तरह के छोटे हथियारों के कारखाने अमेरिका ने लाओस और थाईलैंड में स्थापित किए। इन छोटे हथियारों का निर्यात अमेरिका विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों को करता है। 1961 से 1971 तक अमेरिका ने इन छोटे हथियारों का निर्यात 12 अरब डॉलर से लेकर 45 अरब डॉलर तक किया जो समग्र के कुल अस्त्र व्यापार का दो तिहाई था। कुछ वर्षों पूर्व ही दुनिया में हथियारों का कुल व्यापार 62 अरब डॉलर का था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सारे देश 200 अरब डॉलर से भी अधिक हथियारों के निर्माण और खरीद पर हर साल खर्च करते थे। इसमें से गरीब और विकासशील देशों का हिस्सा केवल 80 अरब डॉलर था। इसका मतलब यह हुआ कि बड़े देश ही हथियारों के फैलाव और निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं।

जहाँ तक आणविक अस्त्रों का प्रश्न है, रूस और अमेरिका के पास इनके बड़े-बड़े भण्डार हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा चीन भी तेजी से अणुशक्ति का स्वामी बनता जा रहा है और इसकी विस्तारवादी तथा युद्ध लोभ-नीति विश्वशान्ति के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत ने अपनी अणुशक्ति का विकास शान्तिपूर्ण उपायों के लिए किया है और इस नीति पर अडिग रहने की वह बार-बार घोषणा कर चुका है लेकिन किसी भी राष्ट्र को 'अपने राष्ट्रीय हित' का सदैव ध्यान रखना होता है और शत्रु-देश भारत को दबाने की नीति छोड़ेंगे, भारत के विरुद्ध अस्त्रास्त्रों के संपर्क में लगे रहेंगे तो इस बात की सम्भावना को नकारना कठिन है कि भारत को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

अस्त्रों के सग्रह और खपत की जो होड़ लगी हुई है उसमें अपनी मूर्खता के लिए विकासशील देशों को अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद

पर खर्च करना पड़ता है। इससे उन देशों में हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहती है। हथियार बनाने वाले ही हथियारों पर रोक लगाने सम्बन्धी बातें करते रहते हैं और ऐसी बातचीत के दौर में ही निःशस्त्रीकरण तथा आणविक हथियारों के विस्तार पर रोक लगाने सम्बन्धी कुछ समझौते भी किए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अन्तिम नतीजा व्यावहारिक रूप से 'वही ढाक के तीन पात' है। लगभग 12 साल पहले निःशस्त्रीकरण समझौते की बातचीत शुरू हुई थी। इस बीच अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के बनने की तादाद पाँच गुनी से भी अधिक बढ़ी है।

शस्त्र और शान्ति¹

(Arms and the Peace)

आज की दुनिया में शस्त्रों की होड़ अपनी चरम सीमा पर है लेकिन कहा जा रहा है कि सब कुछ शान्ति के लिए हो रहा है। लन्दन से प्रकाशित नेशनल रेव्यूजर सोसायटी के फी थिंकर पत्र में पीटर काडोगान ने इस समस्या पर अपने लेख से दुनिया के विवेकशील लोगों से अपील की है कि सेनाओं और शस्त्रों की आवश्यकता पर नए सिरे से विचार किया जाए। उनका विश्वास है कि शस्त्रों का व्यापार करने वाले देशों को यह घृष्टित व्यापार छोड़ने पर विवश किया जा सकता है—

हम आज युद्ध की तैयारियों की स्थिति में रह रहे हैं। कहा यह जाता है कि शान्ति का युग है। युद्ध मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। वह देशों का अभिन्न अंग रहा है। राजनीति बन्दूक के बल पर चलती रही है। यही हमारी उत्पत्ति है कि क्या युद्ध से मुक्ति पाने के लिए सरकार और राजनीति दोनों का ही त्याग कर दिया जाए? और फिर वर्तमान सभ्यता से भी आगे की कोई बात सोची जाए? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमें जब तक देशभक्त बनकर रहना है युद्ध की कल्पना से मुक्त हो नहीं सकते। एक युद्ध समाप्त होगा तो दूसरे की तैयारी में लग जाएंगे। इससे हमारी मुक्ति नहीं है।

प्रायः लोगों को बताया जाता है कि जब राजनीतिक समस्याओं का शान्तिपूर्ण समाधान न निकले तो युद्ध का रास्ता ही अस्तिवार करना पड़ता है। धारणा बन गई है कि सैनिक तरीके अपनाकर समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए युद्ध को अन्तिम विकल्प माना ही जाता है। इसलिए आज की शताब्दी में अस्त्र-शास्त्रों का विकास हो रहा है। लेकिन साथ ही इस विकास से यह परिणाम भी निकलता है कि सैनिक तरीकों से समस्याएँ हल करने की धारणा बिल्कुल गलत है। विषयनाम में अमेरिकियों के पास परमाणु हथियार तक ये जिनका इस्तेमाल कर वे सबका सफाया कर सकते थे। लेकिन ऐसा वे नहीं कर सके। अगर कहीं कर देते तो दुनिया से वे कट जाते। देश में भी सरकार की निन्दा होती। तीसरे, एक ऐसे युद्ध की सम्भावना बढ़ जाती जिसमें हजारों लाखों की तादाद में अमेरिकी भी मरते। ऐसी जोखिम अमेरिका ने नहीं ली। हार मान कर ही वह वहाँ से हट गया।

1957 से अमेरिकियों ने बड़े पैमाने पर वदला लेने की बात कहनी बिल्कुल बन्द कर दी लेकिन उनकी भाषा और हृदय में परिवर्तन किसी कारणवश आ गया था ? ऐसा नहीं है । 1957 में मोवियत सघ अपना स्पुतनिक कक्ष में पहुँचा चुका था । आज पृथ्वी से कोई 600 मील ऊपर साढ़े चार हजार उपग्रह प्रतिदिन चक्कर लगा रहे हैं उनमें देशों की सहायक शक्ति दिलाने की क्षमता है । दो-तीन मील ऊपर से ही यह पता लग जाता है कि कौन देश क्या कर रहा है । पृथ्वी पर चलती हुई मिमी भी मॉटर-कार का पीछा अन्तरिक्ष से किया जा सकता है । पता नहीं आज देश जामूसी की घटनाओं को लेकर इतना हल्ला क्यों मचाते हैं जबकि यह बराबरी अन्तरिक्ष से हो रही है । करदाता का पैसा सबसे अधिक आज इन कामों पर खर्च किया जा रहा है । जगह-जगह देशों की सरकारें लोगों से शान्ति रखने की अपील करती हैं । लेकिन मैनिक शक्ति को दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है । जिस देश के के पास आज अधिकाधिक सैनिक शक्ति है उसी का सम्मान है । यह एक असाधारण स्थिति है । स्वयं सेना को आज अपने से यह पूछना पड़ रहा है कि आखिर उसरी समाज में भूमिका क्या है ?

आज अगर बम, उपग्रह और राकेटों आदि के कारण बड़े राष्ट्रों के लिए युद्ध असम्भव बन गया है तो यह भी मोचना पड़ेगा कि वे सैन्यवाद को किस तरह उचित ठहरा सकते हैं । इन्टर आर्मस् नामक एक फर्म की मैनचेस्टर में छह मजिल इमारत जिसमें विभी के लिए कोई तीन लाख किस्म के हथियार रखे हुए हैं । इसी फर्म के एक प्रमुख हिस्सेदार और इसके अध्यक्ष ने विदेश सम्पर्क समिति के सामने बयान देते हुए कहा था कि अस्त्रों की होड़ विनाशशायी है जिससे एक न एक दिन ऐसा मघर्ष उत्पन्न होगा जिसमें सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी । लेकिन सवाल यही है कि हम होड़ को छोड़ने में पहल कौन करें ?

नोबेल शान्ति पुरस्कार के संस्थापक श्री अल्फ्रेड नोबेल ने अस्त्रों की बमार्दी में ही दुनिया का प्रसिद्ध शान्ति पुरस्कार स्थापित किया था । सन् 1882 में उन्होंने कहा था “अस्त्र-शस्त्र बनाने वाले मेरे कारखाने आप लोगों के सम्मेलनों से बड़ी जल्दी युद्धों को समाप्त कर देंगे । एक दिन आएगा जब अस्त्र-शस्त्रों से लंबे सेनाएँ एक मैकेण्ड में एक-दूसरे को खत्म कर देंगी और फिर यह मसार युद्ध से बाज आकर अपनी मेनाओं को अपना बना देगा । राष्ट्रों को पता ही नहीं है कि उनमें से किस के पास कितनी सहायक शक्ति है । इसलिए वे युद्ध करने में जतराने हैं, लेकिन मेनाओं और अस्त्रों की समस्या का अभी कोई समाधान नहीं निकला है । अस्त्रों का सबसे अधिक व्यापार यूरोप और अमेरिका से होता है । जब तक यह खोन समाप्त नहीं किया जाता युद्ध का भय भी खत्म नहीं होगा । जब हम एक-दूसरे के साथ शान्ति के साथ रहना सीख जाएँगे तो आखिर वह देश किस के हाथ अस्त्र बेचेंगे ? अन्य लोगों की अपेक्षा मुझे तो यही लग रहा है कि वह दिन जरूरी ही आएगा ।”

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता

(International Morality)

समाज के हित एवं उसके सदस्यों की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि

शक्ति को मर्यादित रखा जाए। ये मर्यादाएँ शक्ति के लिए संघर्ष का ही एक भाग नहीं होनी, किन्तु ये तो उस संघर्ष पर व्यक्तिगत सदस्यों की इच्छा से उनके आदेशों या व्यवहार के नियमों द्वारा ऊपर लादी जाती हैं। नैतिकता प्रायः सही व्यवहार को माना जाता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में 'सही व्यवहार' क्या है यह जानना कठिन है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब एक राष्ट्र कदम उठाना है तो दूसरे देश उस कदम के औचित्य एवं नैतिकता को परखते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता के कुछ मापदण्ड तथा व्यवहार के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर एक देश के व्यवहार के प्रति दूसरे देशों में प्रतिक्रिया होती है तथा दृष्टिकोण बनता है। विभिन्न लेखकों द्वारा इन नैतिक मान्यताओं का वर्णन किया गया है जिनका आचरण कर राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ राज्यों के परस्पर सम्बन्धों को शान्तिपूर्ण एवं कम भराजकतापूर्ण बना सकते हैं। ये नियम हैं, जैसे—अपने वायव्यों को पूरा करना, दूसरे के शब्दों पर विश्वास करना, न्यायपूर्ण कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आदर करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का बहिष्कार करना, आदि। इन नैतिक नियमों का सुविधा से अधिक सम्बन्ध नहीं रहता। एक कार्य सुविधाजनक नहीं होता तो भी वह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता द्वारा सही ठहराया जाता है, दूसरी ओर अनेक कार्य सुविधाजनक होते हुए भी अनैतिक माने जाते हैं। इनीचर के मतानुसार अपने देश के संकीर्ण राष्ट्रीय हित के अनुसार कार्य करना सकोएँ सावंधीमिक सत्य का पालन करने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित तथा अधिक नैतिक है।

नैतिक की व्याख्या समय-समय पर बदलती रहती है। प्रत्येक देश अपने व्यवहार को नैतिक सिद्ध करने की कोशिश करता है। 'शक्ति ही औचित्य है' वाली कहावत के अनुसार विजय एवं सफलता प्रत्येक राष्ट्र के किसी भी व्यवहार को नैतिक बना देती है। भाकमणकारी राष्ट्र भी अपने कार्य को उचित समझता है।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता शान्ति एवं युद्ध दोनों ही स्थितियों में मानव-जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहती है। शान्तिकाल में न केवल प्रमुख जनों की धरन् समस्त देशवासियों की रक्षा करना एक देश का नैतिक कर्तव्य होता है। हो सकता है कि इस कर्तव्य के हानिकारक परिणाम भी हों। अल्पसंख्यक जनसंख्या से घेरित रहते हुए भी देश अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। युद्ध के समय भी मानव-जीवन की रक्षा करना अन्तर्राष्ट्रीय नीति का अंग माना जाता है। विजेता राष्ट्र द्वारा हारे हुए राष्ट्र के नागरिकों का संहार नहीं करना चाहिए और न उनको दास बनाना चाहिए। विजेता-राष्ट्र द्वारा विजित राष्ट्रों के लोगों को धर्म-परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। युद्ध के समय नागरिकों एवं सामान्य वस्तियों पर हमबारी न करके केवल सैनिक महत्त्व के अहों पर ही करनी चाहिए। भारत-पाक संघर्ष के समय जब पाकिस्तान द्वारा नागरिक-संस्थानों पर बमबारी की गई तो यह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन ही था।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का जो चित्र हमने खींचा है, वह निम्नांकित शीर्षकों से अधिक स्पष्ट हो सकेगा ।

शान्तिकाल में मानव-जीवन की रक्षा

(*Protection of Human Life in Peace*)

राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अब अमानुषिक कार्यों को अनुचित समझा जाता है । सत्ता की होड़ में लगे हुए देश भी नैतिकता की सीमाओं में आबद्ध हैं और आज सभी सरकारों का कर्तव्य है कि न केवल विशिष्ट व्यक्तियों, अपितु सामान्य जनता की भी सुरक्षा की जाए । प्रो हंस माँगेन्थो ने लिखा है—“वह विदेश-नीति, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जन-संहार को प्रोत्साहित नहीं करती, राजनीतिक समयानुकूलता के कारण इस सीमा को अपने ऊपर थोपती नहीं है । इसके विपरीत इसका लाभ पूर्ण तथा प्रभावशाली कार्य-सिद्धि में होता है । इस सीमा का उद्गम निरपेक्ष नैतिक मिद्धान्त में निहित है और इसका पालन इसके राष्ट्रीय हितों के विपरीत होते हुए भी किया जाना अनिवार्य है । ऐसी विदेश-नीति उस समय राष्ट्रीय हितों का भी त्याग कर देती है, जब राष्ट्रीय हितों के लिए नैतिक मिद्धान्त का उल्लंघन, जैसे कि शान्तिकाल में जन समूह की हत्या का निषेध, आवश्यक हो जाता है ।”

माँगेन्थो का मत है अनावश्यक यातनाएँ और हत्याएँ न करने के कर्तव्य पालन के कारण ही पृथ्वी पर मानव-जीवन विकसित हो सका है । विकास का लक्ष्य किसी ऊँचे ध्येय की प्राप्ति हेतु हो जिसके लिए यातना अथवा नर-संहार आवश्यक नहीं है और इस ऊँचे लक्ष्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय हित भी पूर्ण सम्भव है ।

यदि व्यवहारगत देखा जाए तो आज के युग में शान्तिकाल में मानव-जीवन की रक्षा के नैतिक दायित्व को बहुत कुछ निभाया जाना है । आज एक निरन्तर शासन के लिए भी यह बठिन है कि वह जनता की आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था न करे ।

युद्धकाल में मानव-जीवन की सुरक्षा

(*Protection of Human Life in War*)

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का यह भी तत्वाज्ञा है कि युद्धकाल में जन-माधारण को जीवन की सुरक्षा प्रदान की जाए । इसी मानवतावादी उद्देश्य ने घनेक अन्तर्राष्ट्रीय अभिममयो (International Conventions) को प्रेरित किया है जिनका अनुकरण करके युद्ध के समय जन-माधारण के विनाश को टाला जाता है । इतिहास का अवलोकन करने में स्पष्ट होता है कि जन-जीवन को युद्ध की विभीषिका में बचाने के लिए समय-समय पर युद्ध सम्बन्धी विभिन्न घोषणाएँ की जाती रही हैं । सन् 1856 की पैरिस-घोषणा (The Declaration of Paris 1856) ने समुद्री प्रयवा समुद्रतटीय युद्ध (Maritime Warfare) को सीमित कर दिया था । सन् 1864 की सेंट-पीटर्सबर्ग-घोषणा ने ऐंम हथियारों के प्रयोग को निषिद्ध ठहरा दिया था

जिनसे धातुयुक्त रूप से सफेद और असमर्थ व्यक्तियों के कष्ट बढ़ें। इस घोषणा ने ऐसे प्रलेपास्त्रों के प्रयोग को भी निषिद्ध ठहरा दिया था जिसका वजन 400 ग्राम से कम हो और जिन्हें किसी विस्फोटक पदार्थ से संचालित किया जाता हो। सन् 1899 की हेग-घोषणा (The Hague Declaration of 1899) ने उन डगडम कारतूतों (Dum Dum Bullets) के प्रयोग को निषिद्ध किया था जो मानव-शरीर में प्रवेश करके फैल जाते थे या चपटे हो जाते थे। सन् 1907 के हेग सम्मेलन (The Hague Convention of 1907) ने विष अथवा विषाक्त हथियारों के प्रयोग को निषिद्ध ठहराया था। इस सम्मेलन ने विरोधी राष्ट्रों के व्यक्तियों को धोखा-धड़ी और कूरता से घायल करना भी निषिद्ध ठहराया गया था। आज भी अनेक ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनसे आणविक युद्ध सीमित हो जाएँ। युद्ध-बन्दिनों के सम्बन्ध में भी अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से अनेक प्रयत्न किए गए हैं। सन् 1899 और 1907 के हेग सम्मेलन और सन् 1929 व 1949 के जेनेवा सम्मेलनों में इसकी विस्तार से व्यवस्था की गई है कि युद्ध-बन्दिनों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए।

शासक वर्ग की नैतिकता (Moral ty of Ruling Elite)

प्राचीनकाल से शासकवर्ग की नैतिकता के विषय में विवाद रहा है। उनके व्यवहारों के प्रति उत्तमन्न शकाश्रु का तीनों रूपों में निरूपण किया गया है—उनकी प्रशंसा गाकर, उनकी निन्दा कर अथवा उनके व्यवहारों के शासन तथा शासित के दोहरे मापदण्ड को अलग-अलग। प्रशंसा गाने वालों की यह मान्यता रही है कि “राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता, वह सामान्य व्यवस्था के नियमों में परे है, उसकी इच्छा ही नियम है।” वर्तमान शासनतन्त्र में शासक जन-नेता होता है, वह जनता का प्रतिनिधि होता है अतः उसका व्यवहार स्तुत्य होता है, वह विद्वान्त किन्हीं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। सोरोकिन तथा लिन्डेन के अनुसार, “इन तर्कों की कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सका है और अब भी यह सम्भव नहीं है।” कोई भी विद्वान्त वास्तविक तथा तार्किक रूप से शासकवर्ग के सर्वत्र श्रेष्ठ ‘व्यवहार’ को सिद्ध नहीं कर पाता। इन सिद्धान्तों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। केवल सामाजिक अथवा ऐतिहासिक आधार को वैज्ञानिक आधार मानना आवश्यक नहीं है।

शासकवर्ग के व्यवहार की निन्दा करने वाले शासकवर्ग पर धोखा-धड़ी, भ्रूठ, डोंग, आर्थिक जोपण तथा सत्ता के प्रति मोह के आरोप लगाते हैं। सैनिक शासन में व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं होता। उन पर कभी प्रकार के आदेश ऊपर से आरोपित होते हैं जिन्हें मानने के लिए वह विवश होते हैं। सैनिक समाज में विद्यमान सहकारिता एक अनिवार्यता होती है। शासन-पद्धति का कोई भी स्वरूप क्यों न हो, शासक अथवा शासकवर्ग समाज का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की एक दास जैसी स्थिति होती है। अपने से शक्तिहीन देशों को अपने अधीन करने वाले शासकों ने प्रजा के सुखों का भी ध्यान रखा हो, ऐसी

कोई अनिवार्यता नहीं रही है। सिकन्दर महान्, शार्लमैन, फ्रेडरिक तथा पीटर महान् इस श्रेणी के शासक रहे हैं।

ऐसा भी हुआ है कि देश के किसी भाग के किसी व्यक्ति ने अपनी कुटिलता द्वारा अधिक प्रभावशाली बनकर स्वतन्त्र व्यक्तियों को अपने अधीन रखने का प्रयास किया है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आने पर उन्होंने अपने हितों तथा लाभों को सामान्य जनता के सुखों से अधिक महत्त्व दिया। लॉर्ड एक्टन के अनुसार, "सत्ता मनुष्य को मदान्ध बना देती है".....राजनीतिक दृष्टि से सभी महान् व्यक्ति निम्न चरित्र के व्यक्ति रहे हैं। यदि जनता उनके चरित्र को जान पाती तो उन सबको निश्चय ही पसी पर चढ़ा देती।" पर इन लोअरों को लगाने पर भी यह सिद्धान्त अपने पक्ष में निश्चय दृढ़ तथा तथ्यपूर्ण आधार उपस्थित नहीं कर पाता।

दोहरे मापदण्ड को मानने वाले नैतिक तथा राजनीतिक कार्यों में द्वैत के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। किसी राजनीतिक कार्य के गुण-दोषों का विवेचन नैतिकता के आधार पर नहीं किया जा सकता, ऐसी उनकी मान्यता होती है। राष्ट्र हित में किया गया कोई निन्दनीय कार्य भी नैतिकता के आधार पर निन्दनीय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन के दो स्वरूप हैं— (i) व्यक्तिगत, (ii) राष्ट्रीय। दोनों में कोई समता नहीं होती। सम्भवतः इन्हीं कारणों से प्राचीन शासकों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में कुछ भी करने में सकोच नहीं किया। कोसिमो-डि-मेडिसी (Cosimo-di-med ci) के अनुसार, "अपनी क्रूरता द्वारा शासक अपनी शक्ति का पुनःसंचय करता है। उसके क्रूर कुटिलों से अच्छे समाज की व्युत्पत्ति होती है।"

नैतिकता के दोहरे मापदण्ड के सिद्धान्त को भिन्न-भिन्न युगों में विभिन्न व्यक्तियों ने बल प्रदान करने का प्रयास किया है। मैक्रियावेली के अनुसार, "उत्त शान्त के लिए जो अपनी सत्ता कायम रखना चाहता है, अच्छे न बनने की वृत्ता का परमेश होना आवश्यक है। उसे आवश्यकतानुसार अपने विवेक का उपयोग करना घाना चाहिए।" इसकी और स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, "किसी शासक में नम्रता सद्गुणों का होना प्रशंसनीय है, किन्तु मानवीय सीमाओं के कारण यह सम्भव नहीं है। अतः शासक में उन दुर्गुणों का होना भी आवश्यक है जिनके अभाव में राज्य की रक्षा सम्भव न हो पाए।".....अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कार्यों से पूर्णा पैदा होती है.....। सभी-वर्गीय राज्यतन्त्र को भली-भाँति बसाने के लिए शासक का भ्रष्ट होना आवश्यक हो जाता है। उन शक्तियों के भ्रष्ट हो जाने पर, जिनके अभाव में शासन सम्भव नहीं है, शासक तो भी उनका अनुसरण करना होता है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का किया जाना शासक के लिए अनु उत्पन्न करना है।"

विभिन्न विचारधाराएँ अपने पक्ष तथा अन्य सिद्धान्तों के विरोध में विभिन्न तर्कों उपस्थित करती हैं। इनमें से किसी एक का अच्छा होता विश्वासपाद है।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का मूल्यांकन (Evaluation of International Morality)

निष्कर्ष रूप में यह कहना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के विषय में विचारकों में मतभेद है। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध शक्ति पर आधारित होते हैं। इनमें नैतिकता को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत आदर्श को महत्व देने वाले अवास्तविक विचारकों के अनुसार नैतिकता के नियमों का व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों द्वारा समान रूप से व्यवहार होना चाहिए।

यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार प्राचीन भारत में कौटिल्य के समय से मैकिगवेली और हीगल के समय तक विभिन्न राष्ट्रों के मध्य नैतिकता का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं रहा है। हीगल (Hegel) के अनुसार, "प्रत्येक राष्ट्र अपने में एक पूर्ण इकाई है। राष्ट्रों में सम्भाव अथवा विरोध उनके निजी स्वार्थों को ध्यान में रखकर होता है।" कॅनेथ थॉम्पसन (Kenneth W. Thompson) के अनुसार, "राष्ट्रीय नैतिकता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान नैतिकतापूर्ण दृष्टिकोण की दुर्गन्धनाएँ हैं जिनके मूल में दिखावापन अथवा घोर अहम् है।" राष्ट्र द्वारा की गई घोरणाओं तथा स्वीकृत नीतियों के अनुसार राष्ट्र के नैतिक मूल्यों का निर्धारण होता है। इससे स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नैतिकता को कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

इसके विपरीत आदर्शवादी विचारकों के अनुसार नैतिक नियमों का मूल्य केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्रों के लिए भी है। व्यक्ति तथा राष्ट्र में संचारिक एकता की स्थापना के लिए दोनों द्वारा समान नैतिक मूल्यों का स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय व्यवहार में समान प्रतिष्ठित मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। प्रेसीडेंट विल्सन के शब्दों में, "हम ऐसे युग के प्रारम्भ पर हैं जिसमें राष्ट्रों द्वारा उन्ही व्यवहारों, विचारों तथा मूल्यों को महत्व दिया जाएगा जिनकी सम्पूर्ण देश अपने नागरिकों से अपेक्षा करते हैं।" प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के अनुसार, "राष्ट्रीय नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता की तरह निरन्तर आवश्यक है।"

कसौटी पर कसने पर उपर्युक्त दोनों ही विचारधाराएँ सरी नहीं उतरती। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का अपना विशिष्ट नैतिक स्वरूप है। प्रत्येक निरंकुश शासक के भी अन्य देशों के प्रति अपने निश्चित नैतिक मापदण्ड रहे हैं। प्रोफेसर क्लाउड (Claude) के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ की सभा एक सामान्य म्यूनिसिपल सभा के अनुसार है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य मूल्यों तथा आवश्यकताओं को स्वीकार किया गया है। उनके विचारानुसार अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता पर प्रभावशाली अंकुश न लगाने का मूल कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य समस्याओं का होना है जो अपने सार्वजनिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु नैतिकता के मूल्यों को छोड़ देती है।

अन्त में, यह स्वीकार करना होगा कि आज की बदलती हुई परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का महत्त्व निरन्तर घटता जा रहा है। इसका कारण यह

है कि प्रजातन्त्र के युग में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनैतिक कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जैसा कि अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के राजतन्त्रों के युग में सम्भव था। थॉम्पसन के शब्दों में, "अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता उसी दिन समाप्त हो गई जब शेष ससार द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को शुद्ध लक्ष्य माना गया", और इसमें सन्देह नहीं कि जब पाकिस्तान के तानाशाहों ने पूर्वी पाकिस्तान (अब स्वतन्त्र बंगलादेश) के लाखों नर-नारियों और बच्चों पर अमानुषिक अत्याचार किए तो विश्व के कुछ राष्ट्र मौखिक सहानुभूति दिखाते रहे। अधिक राष्ट्रों ने मौन साध लिया और अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था की संरक्षक कहने वाली विश्व-संस्था (संयुक्त-राष्ट्रसंघ) तमाशा देखती रही। वास्तव में, जहाँ महाशक्तियाँ स्वयं संयुक्त होकर रुचि लेती हो वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता दिखाई देने लगती है; जहाँ महाशक्तियों के हित टकराते हो वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता 'नयी भिन्नारिण' बन कर रह जाती है। छोटे राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की पुकार करते हैं पर "नक्काशखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है?"

विश्व जनमत (World Public Opinion)

आधुनिक युग लोकतन्त्र का युग कहा जाता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकमत का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। लेकिन लोकमत की प्रभावशीलता दोनों स्तरों पर एक जैसी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यावहारिक विश्लेषण यह प्रकट करता है कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर विश्व-लोकमत का प्रभाव पड़ता है, तथापि विश्व-लोकमत की अवहेलना ही अधिक हुई है। विश्व-लोकमत 'शक्ति सम्बन्धों' और 'शक्ति-सर्पण' की धारणाओं से अत्यधिक प्रभावित रहा है और जहाँ कहीं महाशक्तियों में मतभेद होता है वहाँ विश्व-लोकमत की प्रभावशीलता दिखालाई देने लगती है और जहाँ उनमें विरोध होता है वहाँ शेष राष्ट्रों की आवाज कुचल दी जाती है। यद्यपि अब स्थिति पलटनी जा रही है, एशिया और अफ्रीका के स्वतन्त्र राष्ट्रों के उदय ने महाशक्तियों की मनमानी पर कुछ प्रभावी अनुश्रुति लगाया है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि विश्व-लोकमत का व्यावहारिक अस्तित्व है। यदि ऐसा होता तो (1) बंगलादेश में पाकिस्तान भयंकर नर-संहार न कर पाता, (2) दक्षिणी अफ्रीका में 'गोरी चमड़ी' का 'वासी चमड़ी' पर निरन्तर अत्याचार रुक जाता, (3) अस्त्रास्त्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के व्यय को घटाकर विश्व की गरीबी को मिटाने की दिशा में प्रभावशाली प्रयत्न किए जाते तथा विश्व के बहुसंख्य पिछड़े हुए राष्ट्रों की मनोभावनाओं और आकांक्षाओं का सम्मान किया जाता; (4) महान् अन्तर्राष्ट्रीय समस्या संयुक्तराष्ट्र संघ महाशक्तियों के दाव-पेचों की रण-स्थली न बनती और मही रूप में विश्व-लोकमत की आवाज का सम्मान करती; (5) विश्व के बड़े देश दूसरे राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप बन्द कर देने; (6) प्राणविक विस्फोटों द्वारा विश्व के

वातावरण को दूषित न बनाया जाता, (7) विश्व के महासागरो को शक्ति-स्पर्द्धा से उन्मुक्त रखा जाता तथा सैनिक झड़ों का विस्तार न किया जाना; (8) मानव-अधिकारों की रक्षाय रक्षा की जाती और इसी प्रकार के अन्यान्य मामलों पर विश्व की अधिकांश जनता व विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की बात सुनी जाती। बहने का आशय यह है कि विश्व-लोकमत अपना प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य डालता है, लेकिन अधिकांशतः यह निष्प्रभावी सिद्ध होता है या बहुत दीर्घकाल में अपना प्रभाव दिखाता है। जिस तेजी से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रगमच पर अभिनेताओं की भूमिकाएँ बदल रही हैं और महाशक्तियों की 'पकड़ घोर जकड़' ढीली पड़ती जा रही है, शक्ति के अनेक केन्द्रों का उदय हो रहा है, उसे देखते हुए यह आशा की जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व-लोकमत से अधिकाधिक प्रभावित होनी जाएगी। विश्व-लोकमत का बहुत ही यथार्थवादी विश्लेषण हम मॉर्गेन्थो ने प्रस्तुत किया है और हमारा अग्रिम विवेचन अधिकतर मॉर्गेन्थो के विचारों का ही संशेष है।¹

विश्व-लोकमत क्या है ?

(What is World Opinion ?)

कूले के अनुसार लोकमत एक साव्यकी प्रक्रिया है, यह एक विशेष समय में एक विशेष प्रश्न पर सहमति मात्र नहीं है। मॉर्गेन्थो के शब्दों में, "स्पष्टतया विश्व-लोकमत वह लोकमत है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लेता है। वह विभिन्न राष्ट्रों के सदस्यों को कम से कम कुछ मूल अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में एक मतक्य में एकीकृत कर देता है। समस्त विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज की विसाल पर, जो कोई बात इस मतक्य द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उसके विरुद्ध यह मतक्य स्वचालित प्रतिक्रियाओं में अपना अनुभव करा देता है। जब कभी किसी राष्ट्र की सरकार एक निश्चित नीति की घोषणा करती है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर कोई ऐसा कार्य करती है, जो जनमत का उल्लंघन करना है, तो मान्यता, राष्ट्रीय सम्बन्धों की चिन्ता किए बिना, उठ खड़ी होगी। यही नहीं, वह जनमत का उल्लंघन करने वाली सरकार पर स्वचालित अनुशास्त्रियों के माध्यम से कम से कम अपनी इच्छा धोपने का प्रयत्न तो करेगी ही। इस प्रकार वह सरकार फिर स्वयं को लगभग उसी स्थिति में पानी है, जिसमें कि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह, जिन्होंने अपने राष्ट्रीय समाज अथवा इसके उपविभागों में जिनो एक की लोक-नीतियों की अवज्ञा की है। समाज या तो उनको अपने मानकों के अनुरूप बनने के लिए विवश कर देगा अथवा अनुरूपता के अभाव में उनका निष्काशन कर देगा।"²

विश्व-लोकमत की उपर्युक्त व्याख्या के उपरान्त मॉर्गेन्थो ने स्वयं प्रश्न किया

1 *Hans Morgenthau* : Ibid, pp. 250-260.

2 *Morgenthau* : Ibid, p. 251.

है कि—यदि विश्व लोकमत के सामान्य सन्दर्भों का ऐसा अर्थ है तो क्या आजकल ऐसा विश्व-लोकमत अस्तित्व में है और क्या यह राष्ट्रीय सरकारों की विदेश-नीतियों पर अवरोधक प्रभाव डालता है? मॉर्गेंथो के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर निश्चय ही नकारात्मक होगा। आधुनिक इतिहास में ऐसा उदाहरण सम्भवतः नहीं मिलता कि कोई सरकार किसी अघिराष्ट्रीय लोकमत की सहज या स्वेच्छिक प्रतिक्रिया द्वारा किसी विदेश नीति का अनुसरण करने से रुक गई हो। आधुनिक इतिहास में ऐसे प्रयत्न हुए हैं कि किसी सरकार की विदेश-नीति के विरुद्ध विश्व-लोकमत को गतिशील बनाया गया हो, उदाहरणार्थ—तीसरे दशक में चीन के विरुद्ध जापानी आक्रामक कार्यवाहियों, सन् 1935 से जर्मन विदेश-नीतियों, सन् 1936 में इथियोपिया के विरुद्ध इटली के आक्रमण, सन् 1956 में हंगरी-क्रान्ति के रूसी-दमन आदि के विरुद्ध विश्व-लोकमत संगठित करने के प्रयत्न हमारे सामने हैं लेकिन इन प्रयत्नों के परिणाम अन्ततोगत्वा क्या निकले? यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि ये प्रयत्न एक निश्चित मात्रा में सफल रहे और इन प्रयत्नों में एक विश्व-लोकमत का अस्तित्व था, किन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि ये प्रयत्न उन नीतियों का अवरोध करने में सफल नहीं हुए जिनके विरोध में ये संचालित किए गए थे। सही बात यह है कि तथ्यों द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं होती कि ये प्रयत्न किसी सीमा तक सफल रहे थे या उनमें विश्व-लोकमत वास्तव में झलकता था।

मॉर्गेंथो ने पुनः प्रश्न उठाया है कि तब क्या कारण है कि उपर्युक्त प्रश्नों का बहुधा स्वीकारात्मक उत्तर दिया जाता है। मॉर्गेंथो के मतानुसार इसका कारण (1) हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में दो कारकों या तत्त्वों की भ्रामक व्याख्या में डूब सकते हैं जो एक विश्व-लोकमत के सम्भव विकास की ओर संकेत करती हैं और (2) एक तीसरे उस कारण की उपेक्षा में डूब सकते हैं जिससे विश्व-लोकमत का ऐसा कोई भी विकास अमम्भव बन जाता है। मॉर्गेंथो के अनुसार ये तीनों कारण निम्नलिखित हैं—

- (1) विश्व की मनोवैज्ञानिक एकता (Psychological Unity of the World)
- (2) प्राविधिक एकीकरण की अस्पष्टता (Ambiguity of Technological Unification)
- (3) राष्ट्रवाद की अड़चन (The Barrier of Nationalism)

विश्व की मनोवैज्ञानिक एकता
(Psychological Unity of the World)

स्वतन्त्रता, शान्ति और व्यवस्था—ये ऐसी बातें हैं जिन्हें सभी व्यक्ति चाहते हैं और इस प्रकार ये बानें एक प्रकार से विश्व-लोकमत का प्रतीक हैं। इनमें से किसी का भी उल्लंघन विश्व-लोकमत का उल्लंघन समझा जाएगा और यह निश्चित है कि विश्व-लोकमत इन बानों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अपनी तीव्र प्रतिक्रिया

व्यक्त करेगा। मूल रूप में मनुष्य मान की इच्छा का दमन विश्व-लोकमत को स्वीकार नहीं होगा।

विश्व की यह मनोवैज्ञानिक एकता विश्व-लोकमत के विकास को सम्भव बनाती है लेकिन वास्तविकता (Reality) कुछ और ही दर्शाती है। दार्शनिक दृष्टि से तो मानकों की समरूपता (Similarity of Standards) दिखाई देती है—अधिकांश राजनीतिक दर्शन सामान्य भलाई, विधि, शान्ति और व्यवस्था, जीवन, स्वतन्त्रता, सुख की खोज आदि के मूल्यांकन में सहमत है—तथापि नैतिक निर्णयों और राजनीतिक मूल्यांकन में भारी अन्तर दिखाई देता है। एक जैसी नैतिक और राजनीतिक अवधारणाएँ विभिन्न वातावरणों में भिन्न-भिन्न अर्थ ग्रहण करती हैं। एक जगह न्याय और लोकतन्त्र का एक अर्थ लगाया जाता है तो दूसरी जगह बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाने के उदाहरण मिलते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर किसी कार्यवाही को एक समूह अनैतिक और अन्यायपूर्ण ठहराना है तो दूसरा समूह उसी कार्यवाही की प्रशंसा करता है। इस प्रकार एक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों एवं तार्किक उच्चावर्तनाओं में अन्तर है, तो दूसरी ओर सहवर्ती राजनीतिक अनुभवों, सांवांभीमिक नैतिक दृढ़ विश्वासों तथा सामान्य राजनीतिक उच्चाकांक्षाओं का अभाव है। ये बातें विश्व-लोकमत के अस्तित्व को या उसके विकास की सम्भावना को नकारती हैं।¹

श्रीष्टोगिक एकीकरण की अस्पष्टता या संदिग्धता (Ambiguity of Technological Unification)

तकनीकी अथवा श्रीष्टोगिक विकास के कारण विश्व का जनमानस एक दूसरे के काफी निकट आ गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संचार-साधनों में विभिन्न राष्ट्रों के लोगों को एक दूसरे की समझने और सूचित होने का अवसर प्रदान किया है और इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है मानो हम विश्व-लोकमत की प्राप्ति के सन्नित पहुँच गए हैं। मॉर्गन्थो के शब्दों में, “जब हम कहते हैं कि ‘एक विश्व’ (‘One World’) है तो हमारा अभिप्राय केवल यह नहीं होता कि संचार साधनों के वर्तमान विकास ने भौतिक सम्पर्कों तथा मानव-जाति के सदस्यों के बीच सूचना और विचारों की भौगोलिक दूरियों को वस्तुतः मिटा दिया है, बल्कि हमारा यह भी अभिप्राय होता है कि शारीरिक और धार्मिक संचार के इस असीमित अवसर ने सारी मानवता को अपने में समेटने वाले अनुभव की उस साम्य को जन्म दिया है जिससे विश्व-लोकमत का विकास सम्भव हो सकता है।” लेकिन मॉर्गन्थो का विचार है कि, यह परिणाम तथ्यों द्वारा सिद्ध नहीं होता। दो विचार यह तर्कते देते हैं कि नैतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं है जो कि विश्व के प्राविधिक एकीकरण के अनुरूप है। इसके विपरीत, आधुनिक विश्व नैतिक तथा राजनीतिक एकीकरण में उससे भी दूर है जितना कि यह और भी कम अनुकूल तकनीकी परिस्थितियों में था।

सर्वप्रथम आधुनिक श्रीष्टोगिकी (Modern Technology) ने विभिन्न देशों

के बीच संचार साधनों की सुविधाओं के साथ-साथ, उन देशों की सरकारों और प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में भी ऐसी अपूर्व शक्ति सौंप दी है कि वे इस प्रकार के संचार को असम्भव बना दें। 200 वर्ष पहले एक शिक्षित रूसी के लिए फ्रांसीसी राजनीतिक दर्शन और कार्य-पद्धति सीखना वही अधिक सरल था। एक अंग्रेज को जो अपने राजनीतिक विचारों को फ्रांसीसियों में फैलाना चाहता था, आज की तुलना में अधिक अचढ़ा अवसर प्राप्त था। उस समय तक एक स्पेनवासी के लिए उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में प्रवास अथवा वहाँ की यात्रा आज की तुलना में एक अधिक सरल काम था। वास्तव में बात यह है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने न केवल व्यक्तियों के लिए यह सम्भव बना दिया है कि वे भौगोलिक दूरियों के बावजूद दूसरे लोगों के साथ आदान-प्रदान कर सकें बल्कि इन्होंने सरकारी और संचार की प्राइवेट एजेंसियों के लिए ही यह सम्भव बना दिया है कि वे यदि उपयुक्त समझें तो इन संचार साधनों को काट दें। पुनश्च, वहाँ व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था अधिनाशित तकनीकी सम्भावना के क्षेत्र में है। सरकारी और प्राइवेट नियन्त्रण वहाँ एक तकनीकी तथा राजनीतिक वास्तविकता बन गए हैं।

पचास वर्ष पूर्व विदेश भ्रमण के इच्छुक एक अमेरिकी नागरिक के लिए केवल यातायात के साधन की आवश्यकता थी जबकि आज प्रौद्योगिकी विश्व में उसे ऐसा करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा यदि उसके पास उन सरकारी पारपत्र सम्बन्धी कागजों में से एक की भी कमी है जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने देश की सीमा के पार नहीं जा सकता। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इनका कारण आधुनिक प्रौद्योगिकी ही है जिनने अधिनायकवादी या समग्रवादी सरकारों (Totalitarian Governments) के लिए यह सम्भव बना दिया है कि वे अपने नागरिकों को कुछ निश्चित विचारों और सूचनाओं की ही सुराक दें और दूसरों से उन्हें अलग-थलग रख दें। यह भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के ही कारण है कि समाचारों और विचारों का मग्न तथा प्रसार एक विशालकाय व्यापार (A Big Business) बन गया है जिसमें काफी पूँजी की आवश्यकता होती है।

प्रौद्योगिक दृष्टि से आदिम युग में, जबकि मुद्रण हाथ से होता था, कोई भी व्यक्ति अपने साधारण साधनों से पुस्तक या समाचार-पत्र छपा सकता था और उनको वितरित करा कर लोगों के समीप पहुँचा सकता था। लेकिन आज के विश्व में लोगों के वृहत् समूह का अभिव्यक्ति के साधनों पर वही भी प्रभाव नहीं है। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो केवल पर्याप्त साधनसम्पन्न व्यक्ति और संगठन ही जनता तक अपनी आवाज पहुँचा सकते हैं। आज ऐसी बहुत कम सूचनाओं और विचारों को ही लोगों तक पहुँचाने दिया जाना है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रतिबल हैं। स्पष्ट है कि प्रौद्योगिक रूप से हम 'एक विश्व' की बात कर सकते हैं लेकिन नैतिक और राजनीतिक रूप से 'एक विश्व' की बात करना कठिन है।

मॉर्गेंथो का कहना है कि यदि सभार भर में सूचना और विचारों के स्वतन्त्र आदान-प्रदान और प्रसारण की सुविधा होनी तो भी विश्व-मोहमन के अस्तित्व के

प्रति आश्वस्त होना कठिन होता। जो लोग यह विश्वास करते हैं कि विश्व-लोकमत समाचारों और विचारों के स्वतन्त्र प्रवाह का प्रत्यक्ष परिणाम है वे संचरण की तकनीकी प्रक्रिया और संचारित होने वाली वस्तु के बीच अन्तर करने में असफल हैं। वे केवल संचरण की तकनीकी प्रक्रिया से तो सम्बन्ध रखते हैं जबकि संचारित होने वाली वस्तु की उपेक्षा कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि संचारित होने वाली सूचनाएँ और विचार वास्तव में उन अनुभवों के प्रतीक हैं जिन्होंने विभिन्न लोगों के दर्शनो, नीति-शास्त्रों और राजनीतिक अवधारणाओं को ढाला है। यदि ये अनुभव और उनकी बौद्धिक व्युत्पत्तियाँ सारी मानवता में समरूप होनी तो सूचनाएँ और विचारों के स्वतन्त्र प्रवाह से निःसन्देह विश्व लोकमत का निर्माण स्वतः हो जाता। लेकिन, जैसा कि हम देख चुके हैं, वास्तव में अनुभवों की कोई समरूपता या समानता नहीं है जो मानव-समाज को एकता के सूत्र में बाँध सके और यही कारण है कि अमेरिकी, भारतीय और रूसी अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति उसी सूचना या समाचार को अपने विशिष्ट दार्शनिक, नैतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखता है। ये विभिन्न परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण उस एक ही समाचार को अलग-अलग रूपरंग प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ चाहे कोरिया-युद्ध की रिपोर्ट को सें या सन् 1956 की हंगरी-क्रान्ति की रिपोर्ट को सें, विभिन्न पर्ववैधकों की निगाहों में ये रिपोर्ट अलग-अलग बजन रखेगी।

इस प्रकार, माँगियों के अनुसार, यदि हम वास्तव में एक ऐसे विश्व में रह रहे होते जो राष्ट्रीय सीमाओं की कोई चिन्ता किए बिना उन्मुक्त रूप से भ्रमणशील व्यक्तियों, समाचारों और विचारों के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा एकीकृत (Unified) होता, तो भी एक विश्व लोकमत की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। कारण स्पष्ट है और वह यह कि लोगों के मस्तिष्क राजनीतिक भाषाओं के अभाव में पारस्परिक आदान-प्रदान करने में समर्थ होते भी, तो वे एक न होते। यदि अमेरिकी, रूसी और भारतीय एक दूसरे के साथ बोल सकते तो विभिन्न भाषाओं में ही बोलते। यदि उन्होंने एक से ही शब्द कहे होते तो भी उनमें से प्रत्येक के लिए उन शब्दों से भिन्न-भिन्न लक्ष्य, मूल्य और आकांक्षाएँ अभिव्यक्त होती।

राष्ट्रवाद की अडचन

(The Barrier of Nationalism)

राष्ट्रवाद का विचार भी विश्व-लोकमत के निर्माण में एक बाधा है। जब विन्स्टन के 14 सूत्रों (The Fourteen Points) के शब्दों से लोग सर्वत्र सहमत थे, उस समय भी प्रत्येक देश के अपने-अपने विशिष्ट राष्ट्रवाद ने इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ निकाले, उनको अपने विशिष्ट रंग में रंग दिया और उन्हें अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं का प्रतीक बना दिया, और इस प्रकार विश्व-लोकमत जैसी कोई बात सम्भव नहीं हुई। हम समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में देखते हैं कि विश्व में युद्ध की बीभत्सता का विरोध करने और युद्धों को दूर करने की इच्छा

लगभग सर्वव्यापक है। वाशिंगटन, मास्को, पeking, नई दिल्ली, लन्दन, पेरिस और मैड्रिड की सड़कों पर लोग युद्ध के बारे में इसी दिशा में सोचते और बोलते हैं, वे सामूहिक विनाश के आधुनिक साधनों द्वारा लड़े जाने वाले युद्धों की समाप्ति चाहते हैं। लेकिन गहराई से देखें तो वे सब बातें दिखावटी और भ्रामक हैं क्योंकि जहाँ राष्ट्रीय हित की बात उठती है वहाँ लोग युद्ध का विरोध नहीं करते। मानव-जाति के अधिकृत सदस्य चाहे वे अमेरिकी हो या चीनी या अंग्रेजी या इसी युद्धों को अपने विशेष राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं। वे उन युद्धों का विरोध करते हैं जो उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर प्रभाव नहीं डालते जबकि उन युद्धों से मकोच नहीं करते जो उनके राष्ट्रीय हित में होते हैं। संक्षेप में अलग-अलग विशिष्ट राष्ट्रवाद विश्व-लोकमत के निर्माण और विकास में बाधक है। राजनीति के अन्तिम तथ्य राष्ट्र है, मानवता नहीं।¹ राजनीतिक संगठन के हृदय नहीं होता, राजनीतिक मानवता जैसी कोई वस्तु नहीं होती।² ऐसा विश्व-लोकमत जो राष्ट्रीय सरकारों की अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को नियन्त्रित करे केवल एक अभिधारणा है, कोरी कल्पना है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की वास्तविकता ने अभी तक कठिनाई से ही विश्व-लोकमत का कोई लक्षण प्रकट किया है।³ जब कोई राष्ट्र स्वयं को तथा दूसरे राष्ट्रों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसकी विदेश-नीतियाँ सम्पूर्ण मानवता द्वारा सर्वत्र स्वीकृत मानकों के अनुरूप हैं, 'विश्व-लोकमत' अथवा 'मानवता के अन्तःकरण' का आह्वान करती है तो इसका किसी वास्तविकता से सम्बन्ध नहीं होता। विश्व-लोकमत में विश्वास करने वाले यह मूल जाते हैं कि विश्व में हर बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में लोकमत को राष्ट्रीय नीतियों के अभियन्तों की ओर मोड़ दिया गया है।

प्रस्तुत अध्याय के सम्पूर्ण विवरण के उपरान्त निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र की शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएँ लगी हुई हैं। इन सीमाओं के कारण विश्व में व्यवस्था कायम रहती है। यद्यपि यह व्यवस्था अनेक बार भंग हो जाती है जिसमें विश्व-शान्ति के लिए गम्भीर खतरे पैदा हो जाते हैं, किन्तु शक्ति की विभिन्न सीमाओं में से किसी एक अथवा एक से शक्ति के सहयोग से विश्व को विनाश से बचा लिया जाता है। व्यक्तिगत जीवन की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन पर भी इकाइयों का व्यवहार विश्व-समाज की परम्पराओं, रुढ़ियों, मूल्यों एवं विश्वासों द्वारा पर्याप्त प्रभावित होता है। विश्व-शान्ति के लिए परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय शक्ति की इन सीमाओं को सक्रिय एवं प्रभावशाली बनाया जाए।

1 "In politics the nation and not humanity is the ultimate fact."

—Ibid, p 260

2 "The body politics has no heart...There is no such thing as political humanity."

—Ibid, p. 260.

3 "A world public opinion restraining the international policies of national governments is a mere postulate, the reality of international affairs shows as yet hardly a trace of it."

—Ibid, p. 260

अन्तर्राष्ट्रीय विकास और संयुक्त राष्ट्रसंघ (International Development and U. N. O.)

चार्टर की प्रस्तावनाओं में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानव-कल्याण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करेगा तथा नस्ल, विष, भाषा, या धर्म के भेद-भाव के बिना मानव-मात्र के लिए मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतन्त्रताओं की प्रोत्साहन देगा। इस प्रकार चार्टर स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ को अन्तर्राष्ट्रीय विकास के साथ सम्बद्ध कर लेता है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की बनाए रखना तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाना संयुक्त राष्ट्रसंघ का सर्वप्रमुख उद्देश्य है और इनके मूल में भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास का विचार अप्रत्यक्ष रूप से निहित है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के अभाव की स्थिति में किसी भी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विकास की वापस करना व्यर्थ है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों और सिद्धान्तों की रचना ही इस प्रकार की हुई है कि उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की भूमिका तैयार हो और नए नए स्वतन्त्र इस प्रकार स्पष्ट हो कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना तथा मानव-कल्याण के कार्य प्रमुख कर्तव्य समझे जाएँ। संघ के सिद्धान्तों के लिए सदस्य राष्ट्रों की निष्ठापूर्ण स्वीकृति ही नए नए को इस दृष्टि से सक्षम बनाती है कि वह शान्ति एवं सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सीमाओं में रहते हुए हस्तक्षेप कर सके।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाए रखकर अन्तर्राष्ट्रीय विकास का आधार तैयार करना

सब का मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना है। चार्टर के अन्तर्गत यह दायित्व सुरक्षा परिषद् को सौंपा गया है और विशेष परिस्थितियों में महासभा भी इस कार्य में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा स्थापित रखने के लिए मुख्यतः दो प्रक्रियाएँ उपयोग में लाई जाती हैं— शान्तिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाएँ, एवं दमनकारी अथवा बाध्यकारी निर्णयों की प्रक्रियाएँ। इन दोनों ही प्रक्रियाओं का विस्तार से विवेचन अध्याय 10 में किया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रख कर तथा इसे हर सम्भव उपाय से प्रोत्साहन देकर संयुक्त राष्ट्रसंघ उन सभी कार्यों और परिस्थितियों के लिए आधारभूमि तैयार करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास में सहायक है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि वह बिना समय एवं सैनिक कार्यवाही के विवाद को सुलझाने में अपने सद्भाव का उपयोग करे। परतन्त्र लोगों की बहुलवादी को प्रोत्साहित करके संयुक्त राष्ट्र ने अदभुत सफलता प्राप्त की है एवं संयुक्त राष्ट्र के प्रभाव के कारण ही साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सका है। संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व

अपने स्वयं में बड़ी भारी उपलब्धि है जहाँ संधर्षरत राष्ट्र अपने संकुचित दायरे से बाहर आकर अपनी समस्याओं पर उदारता से विचार कर सकते हैं एवं जहाँ पर सम्बन्धित पक्षों को विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा के सन्दर्भ में विवाद के समाधान हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सकता है। यदि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य उसका लाभ उठाना चाहें तो वे निश्चित रूप से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सफलता सदस्य राष्ट्रों के दृष्टिकोण पर आधारित रहती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व में शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने में हर सम्भव सहयोग के लिए प्रस्तुत है परन्तु उसे निर्णयों को स्वीकार कराने की शक्ति प्राप्त नहीं है। सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रों की सद्भावना एवं विश्वास ही उसकी शक्ति है एवं यदि समस्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के प्रति अविश्वास का दृष्टिकोण अपना लेंगे तो निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ अग्रगण्य रह जाएगा।

निःशस्त्रीकरण-प्रयासों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विनाश के लिए वातावरण तैयार करना

अपने सामान्य और सार रूप में निःशस्त्रीकरण की धारणा में विश्व शान्ति और सुरक्षा की सम्भावनाएँ निहित हैं। यदि शस्त्रास्त्रों के निर्माण पर व्यय किया जाने वाला विपुल धन मानव-कल्याण कार्यों पर व्यय किया जाए, संसार से गरीबी को हटाने के लिए किया जाए, विश्व के अभावों को दूर करने के लिए किया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास के शीर्ष पर पहुँचने में विलम्ब नहीं लगेगा। 'शस्त्रों की दौड़' के स्थान पर 'शान्ति के लिए दौड़' शुरू होने पर मानव-समाज की समृद्धि का मार्ग अधिक प्रशस्त होगा तथा विश्व के औद्योगीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नए युग का सूत्रपात होगा। निःशस्त्रीकरण से विश्वराज्य के निर्माण की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी, महायुद्ध का सम्भावित खतरा टल जाएगा तथा राष्ट्रों के पारस्परिक विवाद आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शीत-युद्ध का ज्वर कम हो जाएगा, आतंक के बादल छूट जाएँगे और राष्ट्रों के विवाद बड़ी सीमा तक गोलमेज सम्मेलनों में तय होने लगेंगे। निःशस्त्रीकरण नैतिक रूप से भी आवश्यक है क्योंकि "किसी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य तथा जीवन को रेडियो सक्रिय धूल तथा सामरिक तैयारी द्वारा खतरे में डाले।" संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में निःशस्त्रीकरण को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों की ही कार्यमूर्ची में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 11, 26 एवं 47 में तत्सम्बन्धी व्यवस्थाएँ हैं। प्रारम्भ से ही सध निःशस्त्रीकरण की समस्या पर ध्यान दे रहा है और समय-समय पर निःशस्त्रीकरण की समस्या पर ध्यान दे रहा है और समय-समय पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित करता रहा है। निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयत्नों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विभिन्न आयोग भी नियुक्त किए हैं। संघ के निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रयासों का विस्तार से विवेचन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही के वर्षों में हथियारों की होड़ पर अकुल लगाने के सम्बन्ध

में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं तथा ग्राम एवं पूर्ण निःशस्त्रीकरण की दिशा में कई व्यावहारिक कदम उठाए हैं, यथा सुरक्षा-परिपद् के स्थाई सदस्य-राज्यों के सैनिक बजटों में 10% की कटौती करना और इनके फलस्वरूप बचे धन का एक भाग विकासशील देशों की सहायता के लिए व्यय करना, पर्यावरण परिवर्तन विधियों के सैनिक या किसी अन्य दोषपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना, परमाणु-शस्त्रास्त्रों के परीक्षण पर पूर्ण और ग्राम प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में एक सन्धि तथा जनसंहार के नए प्रकार के हथियारों तथा ऐसे हथियारों की नई प्रणालियों के विकास और निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में एक करार सम्पन्न करना। तीसरी दुनिया के लिए निःशस्त्रीकरण का अपना महत्व है। यदि निःशस्त्रीकरण का प्रयास मकन हो जाए तो इससे तीसरी दुनिया और पश्चिमी देशों में बेकारी की समस्या हल करने, अतिरिक्त रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने और भृजनात्मक तथा उत्पादनशील क्षेत्रों में हथियारों पर व्यय होने वाले धन को लगाना सम्भव होगा। 'विकास के लिए निःशस्त्रीकरण' समय की माँग है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिपद् तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास

संयुक्त राष्ट्रमंडल के छः महत्वपूर्ण भगों में आर्थिक और सामाजिक परिपद् का अपना विशिष्ट स्थान है। आर्थिक एवं सामाजिक परिपद् विश्व के लोगों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में विभिन्न कार्य करती है। यह अपने सहायक भगों द्वारा मानव-जीवन के व्यापक क्षेत्रों का अध्ययन करती है और उस आधार पर व्यापक कदम उठाने की सिफारिशें करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिपद्, महासभा के अधीन, संसार से गरीबी और हीनता को मिटाकर एक स्वस्थ एवं समुन्नत विश्व के निर्माण में प्रयत्नशील है। यदि विभिन्न राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में विवाद हों तो परिपद् उनके समाधान का प्रयत्न करती है और विश्व के चहुँमुखी विकास में सभी देशों के सहयोगपूर्ण दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन देती है।

पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास के लिए इस सस्था द्वारा आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता-योजनाओं का निर्माण किया गया है। परिपद् की प्राविधिक सहायता-समिति का मुख्य उद्देश्य ही दुःख और दरिद्रता से मानव-जाति को मुक्ति दिलाना है। यह अर्द्ध-विकसित देशों को विशेषज्ञ भेजती है और उन्हें मशीनों, यन्त्रों, उत्करणों आदि की पूर्ति के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। परिपद् का मुख्य लक्ष्य मानव-अधिकारों को प्रोत्साहन देना है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए परिपद् द्वारा विभिन्न आयोग स्थापित किए जाते हैं। परिपद् ने शरणार्थियों तथा राज्यहीन व्यक्तियों के लिए निवम बनाए हैं ट्रेड यूनियनों के अधिकारों, उनकी दासता और बेगार का अध्ययन किया है, स्त्रियों की स्थिति एवं सूचना व ट्रेड्स की स्वतन्त्रता पर आयोग स्थापित किया है तथा इन विषयों में विभिन्न समझौतों के प्रारूप तैयार किए हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिपद् के कार्य बड़े

महत्त्वपूर्ण, व्यापक और दूरगामी हैं जिन्हें सम्पन्न करने के लिए अनेक आयोगों, विशेषीकृत अभिकरणों तथा समितियों की स्थापना की गई है। परिपद में आयोगों के दो रूप हैं—कार्यात्मक और प्रादेशिक। प्रथम वर्ग में वित्तीय आयोग, जनसंख्या आयोग, सामाजिक आयोग, मानव-अधिकारों सम्बन्धी आयोग, स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी आयोग, आदि हैं। प्रादेशिक या क्षेत्रीय आयोगों के अन्तर्गत यूरोप के लिए आर्थिक आयोग, एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग आदि उल्लेखनीय हैं। इन आयोगों के अतिरिक्त परिपद में अनेक विशेष अभिकरण स्थापित किये गए हैं, उदाहरण के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व-स्वास्थ्य-संगठन, आदि।

साधारण जनता का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के राजनीतिक और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर अधिक जाता है, जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण एवं सहयोग के कार्य अपेक्षाकृत अधिक ठोस, स्थायी और रचनात्मक होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए जो संगठन हैं उन्हें आधुनिक राजनीतिक जगत में 'प्रकार्यात्मक संगठन' कहा जाता है और इस प्रकार के सहयोग की विश्व शान्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम समझने वाली तो अथवा इस प्रकार की सफलता करने वाली को प्रकार्यवादी अथवा व्यवहारवादी कहा जाता है। ये प्रकार्यवादी संगठन गैर-राजनीतिक होते हैं। प्रकार्यवाद में अन्तर्निहित आधारभूत धारणा यह है कि आर्थिक और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सहयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की समस्याओं को सर्वोत्तम रूप में कम किया जा सकता है। इसमें यह मान्यवादी धारणा भी निहित है कि राज्यों के बीच सघर्ष मुख्यतः सामाजिक असमानता के परिणाम है। आर्थिक लाभों का जो दूषित वितरण होता है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक और सामाजिक बुराइयों ही अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्रों का कारण बन जाती है। इस प्रकार प्रकार्यवाद का मन्देश है कि राजनीतिक क्षेत्र से भी वही अधिक महत्त्वपूर्ण और ठोस कार्य आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग का प्रसार करना है।

समुक्त राष्ट्रमण्डल का कार्य केवल अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना और युद्धों को रोकना ही नहीं है बल्कि उन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निरीक्षण की चेष्टा करना भी है जो सामान्यतः युद्ध का कारण बन जाती हैं। पिछड़े हुए देश गरलता में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार बन कर कालान्तर में विश्व शान्ति को घनरे में डाल देने हैं और समुक्त राष्ट्रमण्डल इस तथ्य को समझने हुए अपनी सीमा में यथासाध्य आर्थिक और सामाजिक सहयोग के प्रसार के लिए प्रयत्नशील है। चार्टर के निर्माता इस तथ्य को भलीभाँति जानते हैं कि विश्व शान्ति को स्थायी तभी बनाया जा सकता है और समुक्त राष्ट्रमण्डल जैसी विश्व सत्ता अपने उद्देश्यों में तभी सफल हो सकती है जब सगार में पिछड़े और विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसलिए राष्ट्रों में आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को यथासाध्य कम करने के लिए

चार्टर के अनुच्छेद 55 में स्पष्टतः व्यवस्था है कि “स्यायित्व तथा कल्याण की दशाओं के निर्माण की दृष्टि से जो लोगों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धान्तों पर आधारित राष्ट्रों के बीच शान्तिप्रिय एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए आवश्यक हैं” संयुक्त राष्ट्रसंघ निम्नलिखित बातों को प्रोत्साहन देगा—

- (क) जीवन के उच्च स्तर तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दशाएँ ।
- (ख) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं सम्बन्धित समस्याओं का समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी सहयोग ।
- (ग) जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म का कोई भेदभाव किए बिना मानव-अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं के लिए सार्वदेशिक मूल्यों का तथा पालन ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत अनेक अभिकरणों की स्थापना की गई है ।

विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास

संयुक्त राष्ट्रसंघ के परिवार में अनेक ऐसी एजेंसियाँ और सस्थाएँ हैं जो विश्व के विभिन्न देशों की जनता के रहन-सहन के स्तर को जैसा उठाने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, बालकों तथा शरणार्थियों जैसे विशेष वर्ग को सहायता पहुँचाने और आर्थिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के लिए विभिन्न देशों की सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं । संघ के चार्टर में मानवीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी आदि कार्यों को बहुत महत्व दिया गया है और इनके निर्वहन के लिए ही विभिन्न विशिष्ट अभिकरणों का निर्माण हुआ है । इन विशिष्ट अभिकरणों का निर्माण पृथक् रूप से हुआ है और ये स्वायत्तगामी सङ्गठन हैं । इनकी स्थापना विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी समझौतों के अनुसार की गई है । इन अभिकरणों को संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बन्धित करने के लिए समझौते के बारे में बातचीत और पर-अवधार, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की एक स्थायी समिति द्वारा की जाती है । इस समिति द्वारा जो समझौते किए जाते हैं उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् महामन्त्र तथा सम्बन्धित अभिकरणों की शाखा विशेष स्वीकृत करनी है । इन अभिकरणों के विभिन्न कार्यों में समन्वय अथवा तात्कालिक रखने का दायित्व आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् पर है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सङ्गठन, मुद्राकोष विश्व-बैंक आदि के अभिकरण हैं जिनका मुख्य उद्देश्य विश्व में हर सम्भव उपाय से आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करना है । इन अभिकरणों द्वारा जो महत्वपूर्ण दायित्व निभाए जाते हैं, उनमें अन्तर्गतता विश्व-जालि और सुरक्षा की अभिवृद्धि सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रमन्त्रीय महान् उद्देश्य की महानता मिलती है । यह कहना चाहिए कि ये अभिकरण संयुक्त राष्ट्रसंघ के

गोद लिए हुए वे सपूत हैं जो अपनी माता के गौरव को बढ़ाने में और उसके उद्देश्यों की पूर्ति में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहायक बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। वास्तव में यह कहना उपयुक्त होगा कि राष्ट्रोत्तर मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने का उपयोगी कार्य समुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बन्धित ये विभिन्न स्वायत्तशासी गैर-राजनीतिक संगठन करते हैं। विभिन्न राष्ट्र इनके सदस्य होते हैं जो परस्पर मिलकर एक-दूसरे के हित की बात सोचते हैं और तदनुकूल कार्य करने की चेष्टा करते हैं। डेविड मिट्रेनी (David Mitrany) के शब्दों में, "दार्शनिक अथवा प्रकार्यात्मक आधार यह है कि इन स्वायत्तशासी संगठनों की विभिन्न गतिविधियों द्वारा सम्पूर्ण प्रशासन के अन्तर्गत सामान्य हित के कार्यों में लगे रहने के कारण, शान्त-शान्त राष्ट्रों की नीमान्त रेखाएँ सारहीन हो जाएंगी और लोग राष्ट्रोत्तर दृष्टिकोण से सोचने-विचारने के अभ्यस्त होकर अन्तर्राष्ट्रीय हित में कार्य करने लगेंगे।" यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से अथवा दार्शनिक आधार पर हम उपर्युक्त दृष्टि की उपेक्षा नहीं कर सकते, तथापि तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसें तो यह स्पष्ट है कि राष्ट्रोत्तर निष्ठाओं का निर्माण प्रायः इस प्रकार नहीं हो पाता है। राजनीतिक हित में संघर्ष होता है तो इन अन्तर्राष्ट्रीय स्वायत्तशासी गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों और उद्देश्यों तथा राष्ट्रीय हितों में संघर्ष नहीं होता, तभी तब सामान्यतः राष्ट्रोत्तर भावनाओं का मूल्य प्रभावी रहता है अन्यथा दोनों में संघर्ष की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की कीमत पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती है।

निम्नांकित विशिष्ट अभिकरण आर्थिक बल्याण के विकास और प्रसार में सहयोगी बनकर विश्व के राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग और सम्पर्क की दृढ़ आधार-शिलाएँ रख रहे हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I L O)—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन समुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अभिकरणों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है जिसका बापेंश्रेष्ठ अर्थ सभी अभिकरणों से विशाल है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल, 1919 को वर्साय की संधि के भाग 13 के अनुसार श्रमिकों के हित-साधन की दृष्टि से की गई थी। समुक्त राष्ट्रसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार इस संगठन ने विश्व के देशों में श्रम एवं सामाजिक कार्य सम्पन्न करने का दायित्व लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन का उद्देश्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा श्रमिकों की दशा उत्थान की जाए, उनकी आर्थिक स्थिति में गिरता लाई जाए और सामाजिक क्षेत्र में उनका स्तर उत्थत बनाया जाए। यह संगठन इस विश्वास पर आधारित है कि सार्वजनिक और स्थायी शांति की स्थापना सामाजिक न्याय की आधारशिला पर ही सम्भव है और श्रमिकों को सामाजिक न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब वे दूसरे लोगों के समान ही आर्थिक बल्याण और उत्थति के मार्ग पर अग्रसर हों। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के मौलिक मिद्दान्त ये हैं—

1. श्रम को वस्तु नहीं माना जा सकता,
2. दरिद्रता नहीं भी हो, सर्वत्र समृद्धि के लिए खतरा है,
3. निरन्तर प्रगति के लिए आवश्यक है कि अभिव्यक्ति और संगठन को स्वतन्त्रता प्रदान की जाए, एवं
4. अभाव और दरिद्रता के विरुद्ध प्रत्येक देश में सम्पूर्ण उत्साह के साथ समर्पण किया जाना चाहिए।

सभी उद्देश्यों, कार्यक्रमों और मौलिक सिद्धान्तों का निचोड़ इस बात में है कि अन्तर्राष्ट्रीय सुख एवं शान्ति के लिए श्रमिकों की स्थिति को हर प्रकार से उन्नत बनाया जाए, उनका आर्थिक विकास किया जाए और उन्हें आर्थिक शोषण से मुक्त किया जाए। आर्थिक विषमताओं से मुक्ति प्राप्त करने पर ही श्रमिकों का आर्थिक स्तर ऊँचा उठेगा, वे जीने योग्य जीवन बिता सकेंगे और जब आर्थिक सुख-समृद्धि का प्रसार होगा तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के प्रसार में सहयोग मिलेगा।

इस संगठन का सर्वप्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक समझौतों तथा सिफारिशों के रूप में श्रम एवं श्रमिकों सम्बन्धी विविध प्रकार की दशाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों का निर्माण करना है, अर्थात् इसका प्रयत्न रहा है कि संसार में हर देश और समाज के श्रमिकों के श्रम का मूल्य और महत्त्व समान हो तथा सामाजिक जीवन में उनके स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक समझौतों और सिफारिशों को सम्मिलित रूप से 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संहिता' (International Labour Code) कहा जाता है। संगठन में जिन समझौतों और सिफारिशों को स्वीकार किया गया है उनमें से कुछ में श्रमिक स्वतन्त्रता के अधिकार, दिन में 8 घण्टे काम, वेतन की सुरक्षा और संवेतन अवकाश की व्यवस्था है, तो कुछ में बालकों और स्त्रियों से कठोर श्रम लेने, स्त्रियों में स्त्रियों को काम पर लगाने तथा बेगार लेने के काम को वर्जित किया गया है। यह संगठन श्रमिकों की दशाएँ सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक अनुसन्धान करता है, प्रांकड़े तथा रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह अमेरिका, एशिया और यूरोप में समय-समय पर क्षेत्रीय अधिवेशन आयोजित करता है तथा विश्व के प्रधान उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार, श्रमिक और मालिकों के त्रिदलीय सम्मेलन आमन्त्रित करता है।

अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का अनुसरण करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने उन्नत श्रम-मापदण्डों के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार निश्चित करने के साधन के रूप में सामान्य आर्थिक विकास की दिशा में हाल ही के वर्षों में अपने प्राविधिक सहायता कार्यक्रमों का विकास किया है। दो महायुद्धों से घबस्त आर्थिक व्यवस्था के सुधार पर पुनर्निर्माण हेतु इस संगठन ने बहुत-से देशों को सहायता प्रदान की है। इतने विभिन्न प्रकार के दार्शनिक कार्यक्रमों का विकास किया है तथा शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना की है। इसने प्राविधिक सूचनाएँ प्रदान की हैं, परामर्श गोष्ठियाँ आयोजित की हैं, छात्रवृत्तियाँ दी हैं तथा व्यावसायिक शिक्षण-संस्थाओं

की स्थापना में विशेष रुचि प्रदर्शित की है। इसने श्रमिकों, मालिकों और सरकारों को यथामुम्भव परामर्श दिया है कि किस तरह अधिक और अच्छा माल उत्पादित किया जाए। विभिन्न देशों में जीवन-स्तर ऊँचा करने, श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ाने, बेकारी को रोकने के बारे में भी इसने सलाह दी है। सहकारिता, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में इसके द्वारा विभिन्न राज्यों को दिए गए परामर्श बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इस संगठन में विभिन्न सरकारों के उन नियमों को निरस्त कराने की चेष्टा की है जिनके कारण घने बसे हुए देशों से अल्प-विकसित देशों को तथा श्रम-शक्ति की कमी वाले स्थानों को श्रमिकों के जाने में बाधा पड़ती है। विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चीन, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, टर्की, यूगोस्लाविया, मिस्र, थाईलैण्ड, बर्मा आदि में इस संगठन द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन ने कारखानों में काम करने वालों के लिए अनेक संहिताएँ तैयार की हैं, जैसे बोयले की खान में काम करने की संहिता, कारखानों के कार्यकर्त्ताओं से सम्बन्धित संहिता आदि। इसमें कोई मन्देह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के प्रयत्नों के फलस्वरूप संसार में श्रमिक समस्याओं के प्रति जागृति उत्पन्न हो गई है और श्रमिकों की दशाओं को सुधारने के लिए कानूनात्मक कानून बनाए जा रहे हैं। इसने 'सामाजिक न्याय' को अनिवार्य की लहरो और प्रतिस्पर्धावाद के प्रभुत्व से बन्धन-मुक्त कर दिया है। यह संगठन आज एक विश्वव्यापी संस्था बन गया है जिसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को 'श्रम की विश्व-समद' (World Parliament of Labour) की सजा दी जाती है। श्रमिक कल्याण के लिए साराहीन प्रयास करने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन की विशेष रूप से आलोचना की जाती है कि यह अपने व्यवहार में निष्पक्ष नहीं रहा है प्रथम इसने जर्जरतमन्दों या अपेक्षाकृत कम जर्जरतमन्दों की अधिक सहायता की है। उदाहरणार्थ, इसने पश्चिमी देशों की ओर अधिक ध्यान दिया है तथा एशिया और अफ्रीका के विछड़े हुए देशों की ओर कम। पुनश्च, यह संस्था इतने अधिक समझौते और सिफारिशों निरूपित करती जाती है कि उन्हें स्वीकार करना तथा उन सब पर प्रभावशाली रूप से क्रमल कर्ना आज की जटिल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों में सम्भव नहीं है।

भारत प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन का सदस्य रहा है। एक प्रमुख राष्ट्र होने के नाते यह देश संगठन की प्रबन्ध समिति का भी सदस्य है। अभी तक भारत संगठन के दर्जनों समझौतों का समर्थन कर चुका है, तथापि बहु-संख्यक समझौते, जो श्रम संगठन ने स्वीकार किए हैं भारत में लागू होने के उपयुक्त नहीं समझे गए हैं। ऐसे समझौते पश्चिम के शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रों के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.)—प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के बीच विश्व के विभिन्न देशों में यह अनुभव किया गया कि आर्थिक दशा को

मुधारने के लिए और राजनीतिक मनमुटाव के आर्थिक कारणों को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग नितान्त आवश्यक है। यह समझ लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक और वित्तीय क्षेत्र में जो अस्त-व्यस्त स्थिति व्याप्त है और विश्व-बाजार में जो कठिनाइयाँ छापी हुई हैं, उन्हें दूर करने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण कदम उठाया जाना चाहिए। इसी अनुभूति के फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम दिनों में ब्रेटनवुड्स अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-सम्मेलन (जुलाई, 1944) ने युद्ध के आर्थिक कारणों को दूर करने की एक योजना तैयार की जिसे दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग में एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया और दूसरे भाग में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (World Bank) की स्थापना की बात कही गई।

दिसम्बर, 1945 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सम्म्याएँ अस्तित्व में आईं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कई उद्देश्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार और सन्तुलित प्रगति का समायोजन था। साथ ही, इसका ध्येय इसे विनिमय की अस्थायी दरों के कुप्रभावों से बचाना और विदेशी विनिमय के प्रतिबन्धों को ढीला करना भी था। इसके अतिरिक्त यह प्रत्येक देश में वास्तविक आय एवं रोजगार के उच्च स्तरों की स्थापना के लिए भी प्रयत्नशील था।

सम्मेलन के अनुच्छेद 1 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के विभिन्न लक्ष्यों की ज्यष्ट किया गया है। इसमें मुख्य रूप से तीन लक्ष्यों को मान्यता प्रदान की गई है—

1. विनिमय-स्थायित्व को प्रोत्साहन देना, सदस्यों के बीच व्यवस्थित विनिमय प्रबन्धों की स्थापना करना और प्रतिस्पर्धा विनिमय मन्दी की स्थिति को दूर करना।
2. सदस्यों के बीच ऋण लेन-देन में सुगमता की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना तथा विदेशी विनिमय के उन प्रतिबन्धों को समाप्त करना जो विश्व व्यापार की प्रगति में बाधक हैं।
3. पर्याप्त सुरक्षाओं के अधीन सदस्यों को कोष के साधन उपलब्ध कराना और इस तरह उनमें विश्वास की भावना जाग्रत करना। इस प्रकार विभिन्न देशों की राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्नता के लिए हानि पहुँचाने वाले प्रयासों को अपनाए बिना ही उनके सुगमता सन्तुलनों की अव्यवस्था को दूर करने का अवसर देना।

मुद्रा कोष के द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति के अतिरिक्त सुगमता-सन्तुलन की विषमता को दूर करने के लिए असन्तुलन की अवधि व अंश को कम करने के लिए, लाभदायक उद्योगों में दीर्घवालीन पूँजी की सहायता प्रदान करने लिए तथा ऐसे ही अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं।

मुद्राकोष के पक्ष-विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया है। एक ओर इसके अनेक लाभ निस्मिद्ध रूप से प्रकाश में आए हैं, तो दूसरी ओर इसकी कार्यविधि और

इसके व्यवहार पर अनेक आक्षेप किए गए हैं। लाभ की दृष्टि से मुद्राकोष के पास विभिन्न देशों की मुद्राओं का भारी स्टॉक एकत्रित हो जाता है जिससे वह सदस्य-देशों की विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मुद्राकोष बहुपक्षीय व्यापार तथा मुग्तान प्रणालियों को बहुत प्रोत्साहन देता है और सदस्य-देशों के मुग्तान शेष में होने वाले तत्कालीन असन्तुलन को दूर करने में सहायता करता है। मुद्राकोष के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं पर विचार-विमर्श एवं सहयोग के लिए एक स्थायी संस्था अस्तित्व में आ गई है। कोष के प्रयत्नों से प्रतिस्पर्धापूर्ण मन्दी का बहिष्कार और विनिमय दर का स्थायित्व आदि सिद्धान्तों को मामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है। अव्यवस्थित विनिमय सम्बन्धों को कम करने की दिशा में भी कुछ सफलता प्राप्त हुई है। इन लाभों को प्रदान करते हुए भी मुद्राकोष द्वारा सदस्य-देशों की आन्तरिक आर्थिक व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो अपने-आप में एक बड़ी बात है। इस कोष की स्थापना से विश्व के देशों को स्वर्णमान के लाभों की प्राप्ति हुई है। कोष की सेवाओं के कारण ही प्रो. होम ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक (International Reserve Bank) की संज्ञा दी है।

बहुमूल्य सेवाओं के बावजूद अनेक कारणों से मुद्राकोष की आलोचनाएँ की गई हैं। आरोप है कि मुद्राकोष अपने मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत कुछ असफल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र में अभी तक वही व्यवस्था कायम है जो कोष ने केवल संक्रमणकाल के लिए स्थापित की थी। अभी तक न तो मुग्तानों की बहुपक्षीय व्यवस्था स्थापित हो पाई है और न ही विश्व-व्यापार की प्रगति में बाधा डालने वाले विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्ध अधिक कम हो पाए हैं। मुद्राकोष का कार्य-क्षेत्र सीमित है। यह केवल चानू सीदो से उत्पन्न असन्तुलन मुग्तानों की समस्या का ही समाधान करता है। युद्ध श्रृंखला की प्रदायगी, पूँजी के आयात-निर्यात, अवधि-स्टलिंग आदि से इस कोष का कोई सम्बन्ध नहीं है और इस मुग्तान के लिए यह सदस्य-देशों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देता। एक गम्भीर आरोप यह है कि मुद्राकोष का सदस्य-देशों के साथ व्यवहार भेदभावपूर्ण है। यह पिछड़े तथा अल्पविकसित देशों की तुलना में विकसित पाश्चात्य देशों को विशेष रियायतें देता है। इन आलोचनाओं में कुछ वजन है और मुद्राकोष आशा के अनुरूप सफल नहीं हो पाया है तथापि यह स्वीकार करना होगा कि इसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। अनुसन्धान एवं परामर्श के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण सेवाएँ की हैं।

विश्व बैंक—अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसे बड़प्पा विश्व-बैंक कहा जाता है, की स्थापना भी जुलाई, 1944 में ब्रिटेनबुद्धस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ ही हुई थी और जून, 1946 में इसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। मुद्राकोष की स्थापना का मुख्य नक्ष्य सदस्य-देशों की मुग्तान सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना था जबकि विश्व-बैंक की स्थापना प्रायः इसनिष्ठ

की गई थी कि युद्धजनित आर्थिक अव्यवस्था को दूर किया जा सके और विकसित तथा अर्थविकसित देशों को दीर्घकालीन ऋणों के रूप में सहायता दी जाए ताकि वे प्रगति और पुनर्निर्माण के पथ पर अग्रसर हो सकें।

विश्व-बैंक की स्थापना के मुख्यतः निम्नलिखित चार उद्देश्य हैं—

1. बैंक का प्रथम उद्देश्य युद्ध द्वारा विनष्ट तथा अर्थविकसित देशों को दीर्घकालीन ऋण देकर उनके पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है।

2. विश्व-बैंक व्यक्तिगत विनियोगकर्ताओं को अर्थविकसित देशों में उत्पादन कार्य के लिए पूँजी का विनियोग करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

3. विश्व-बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है।

4. युद्ध के समय की आवश्यकताओं की प्रकृति शान्तिकाल की अपेक्षा भिन्न होती है। युद्ध के बाद यह आवश्यकता महसूस हुई कि उस समय की आर्थिक व्यवस्था को शान्तिकालीन आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए। यह कार्य विश्व-बैंक करता है।

विश्व-बैंक को उपयोगिता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसके द्वारा 30 सितम्बर, 1965 तक की 20 वर्ष की अवधि में ही लगभग 9,000 मिलियन डॉलर के ऋण प्रदान किए गए जो लगभग 80 विभिन्न उधारकर्ता देशों में लगभग 430 ऋणों के रूप में फँसे हुए थे। बैंक सदस्य-देशों को केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही ऋण देता है। बैंक के ऋणों से अर्थविकसित देशों के विद्युत-शक्ति तथा परिवहन साधनों का अन्धा विकास हुआ है। बैंक ने कृषि-विकास, शिक्षा तथा परिवार नियोजन के लिए भी ऋण देना शुरू कर दिया है। यह सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान भी करता है। सदस्य देशों को तकनीकी मशीन भेजकर वहाँ की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और देशों की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में विश्व-बैंक का उल्लेखनीय योग रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Financial Corporation) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संधि (International Development Association) भी विश्व-बैंक से सम्बन्धित है। वर्तमान संस्था का उद्देश्य सदस्य देशों में पूँजी व्यवसायों को प्रोत्साहित करना तथा दूसरी संस्था के पिछड़े तथा अर्थविकसित देशों में आर्थिक सहायता देकर उनका औद्योगिक विकास करना है। विश्व-बैंक ने सदस्य देशों के पारस्परिक आर्थिक विवादों का निपटारा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अपने छोटे से जीवनकाल में विश्व-बैंक ने प्रशंसनीय कार्य किया है, तथापि कतिपय मापदण्डों पर उसकी कार्यप्रणाली और भूमिका आलोचना का विषय बनी है। कहा जाता है कि विश्व-बैंक प्रायः ऋणी देशों के पक्ष में तथा ऋणदाता देशों के विपक्ष में कार्य करता है। इसके निर्णयों पर ऋणी देशों का अधिक प्रभाव पड़ता है, पर इस आलोचना में ज्यादा वजन नहीं है क्योंकि विश्व-बैंक तो सदस्यों के समुक्त और व्यक्तिगत गारण्टी के सिद्धान्त के आधार पर ही काम करता है। किसी भी

मदम्य देशों को ऋण देने की जोखिम का भार सभी देशों पर पड़ता है। दूसरा आरोप यह लगाया जाता है कि बैंक का कार्य निजी निवेशकर्ताओं द्वारा कहीं अधिक अच्छे ढंग से सम्पन्न किया जा सकता है। यह आलोचना इस दृष्टि में उचित प्रतीत नहीं होती कि विश्व पूंजी निवेशकर्ताओं से कोई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं है। तीसरा आरोप यह है कि विश्व-बैंक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है और प्रायः अमेरिका तथा यूरोपीय देशों का ही अधिक पक्ष नेता है। यह आरोप बहुत कुछ सत्य है। वास्तव में विश्व-बैंक पर इन देशों का पर्याप्त प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। इस चौथी आलोचना में भी वजन है कि विश्व-बैंक द्वारा अंजी व्याज दरें कम की जाती हैं। बैंक का उद्देश्य तो अधिकाधिक देशों को कम व्याज की वित्तीय सहायता देना होना चाहिए।

अन्तिम मूल्यांकन के रूप में बैंक के लाभों का पलड़ा ही अधिक भारी रहता है। विश्व-बैंक ने पिछड़े और अल्प-विकसित देशों के विकास में निश्चित रूप में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है तथा अन्तर्राष्ट्रीय निवेश का प्रवाह बढ़ाने में अपना यथोचित अज्ञान दिया है। बैंक ने यह निश्चित कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक महयोग का विचार बोरी कल्पना न होकर एक स्पष्ट यथार्थता है।

नवम्बर, 1946 में ही भारत विश्व-बैंक का मुख्य सदस्य है। बैंक के प्रशासकीय मंचान्वय मण्डल में भी भारत को स्थायी स्थान प्राप्त है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियावृत्ति में विश्व-बैंक की सहायता काफी महत्वपूर्ण रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (I. D. A.)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास मण्डल विश्व-बैंक में सम्बन्धित है। इसकी स्थापना मिनम्बर, 1960 में की गई थी। अल्प-विकसित देशों को आमान शर्तों पर ऋण देने के लिए ही इस नई संस्था की स्थापना की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास मण्डल का उद्देश्य अल्पविकसित देशों को पश्चिमत, विद्युत-संचार, मिचार्ट, बाढ़-नियन्त्रण आदि के लिए ऋण प्रदान करना है। यह मदम्य देशों को आवास-गृहों के निर्माण, पेयजन की आपूर्ति, स्वास्थ्य, भविष्य आदि में सम्बन्धित योजनाओं के लिए भी ऋण देता है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय विकास मण्डल विश्व-बैंक के पूरक के रूप में अविकसित मदम्य देशों को आर्थिक विकास के लिए मन्ता दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। इन पर व्याज की कम दर कर ली जाती है। दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान देश की मुद्रा में ही किया जाता है।

आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ का विशेष कोष—संयुक्त राष्ट्र के इस विशेष कोष की स्थापना 1 जनवरी, 1959 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े तथा अल्पविकसित देशों को आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी विकास के लिए यथामुम्भव सहायता प्रदान करना है। कोष का प्रबन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ के हाथों में है। कोष द्वारा समय-समय पर निश्चित उद्देश्यों के लिए भारत को ऋण प्राप्त होने रहे हैं।

व्यापार विकास सम्मेलन—व्यापार और विकास सम्बन्धी मयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना कुछ ही वर्षों पूर्व सन् 1964 में हुई थी। इस सम्मेलन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर करना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है। यह सम्मेलन राष्ट्रो को आपस में प्रतिस्पर्धा से बचाता है तथा उन्हें अविकाशिक निर्यात के लिए प्रोत्साहित करता है।

संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम—संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम 1966 से चालू है। यह विकासशील देशों की आर्थिक सम्भावनाओं और उनके सर्वोत्तम उपयोग की योजना बनाने हेतु आवश्यक सर्वेक्षण और अध्ययन करता है। इस प्रकार विरासत कार्यक्रम की महती उपयोगिता है। वर्तमान में संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 10 हजार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ लगभग 130 से भी अधिक देशों में विकास परियोजनाओं में कार्यरत हैं। ये परियोजनाएँ बड़ी व्ययसाध्य हैं। इन पर करोड़ों डॉलर का व्यय होता है। यह व्यवस्था है कि जिन देशों में इन परियोजनाओं पर कार्य हो रहा हो, उन्हें परियोजना का कुल आधा व्यय देना पड़ता है।

मूल्योक्त—विशेष एजेंसियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है एवं सैद्धान्तिक रूप से उनका कार्य सराहनीय है। सौख्यिकी क्षेत्र में इनका कार्य उपयोगी है। एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण होता है। विशेष एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण अधिक सम्पूर्ण एवं व्यापक होने हुए भी इतने स्वतन्त्र नहीं होते जितने निजी अध्ययन द्वारा। विशेष एजेंसियों की बैठकों के बाद-विवादों में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रभाव डाला जाता है परन्तु कभी-कभी उनसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में झड़न भी पड़ने लगती है क्योंकि वाद-विवादों को प्रचार का माध्यम बना लिया जाता है। विशेष एजेंसियों द्वारा ऐसे प्रारूप एवं समझौते तैयार किए जाते हैं जिन्हें सदस्य-राष्ट्र सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन में यह पद्धति बहुत उपयोगी प्रतीत होती है।¹ प्रगतिशील राष्ट्रो को दी जाने वाली सहायता का कुछ अंश इन एजेंसियों द्वारा दिया जाता है। उन्नतिशील राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर अविवक्षित राष्ट्रो की सहायता करते हैं, अमेरिकाने मार्शल योजना द्वारा युद्ध पीड़ित राष्ट्रो को आर्थिक सहायता दी थी। राष्ट्रकुल के उन्नतिशील राष्ट्रो ने कोलम्बो योजना द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रगतिशील देशों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की। नवीली तथा हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर नियन्त्रण, सक्कामक बीमारियों पर नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रीय डाक तथा तार सेवाओं की उन्नित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संचालन की व्यवस्था, विश्व श्रुतु-विज्ञान, सर्वेक्षण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर ही किए जा सकते हैं। अनेक राष्ट्रो के साधनों का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के साधन हेतु विशेष एजेंसियों द्वारा ही सम्भव है। महान् राष्ट्रो की अपेक्षा छोटे-छोटे राष्ट्रो का सहयोग अधिक हितकर

प्रमाणित हुआ है। विशेष एजेंसियों के अन्तर्गत सहायता देने वाले राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय साख तथा प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा जो बड़े राष्ट्र विशेष एजेंसियों के माध्यम से सहायता न कर अलग से सहायता व सहयोग करते हैं, उनकी इसलिए आलोचना की जाती है कि बड़े राष्ट्र अपनी सहायता के माध्यम से अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली अधिक सहायता को स्वाभिमानी राष्ट्र प्रस्वीकार भी कर देते हैं। विशेष एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सहायता का दुष्प्रयोग सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी सहायता अविकसित राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखकर दी जाती है एवं इसके साथ किसी भी बड़े राष्ट्र से सहायता स्वीकार करते समय अनुचित आधार का अनुभव नहीं करते। आज के वैज्ञानिक युग में विशेष एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सहायता अनिवार्य होनी जा रही है। पिछड़े तथा अविकसित राष्ट्र अपनी भूख, दरिद्रता, पिछड़ेपन तथा अशिक्षा को दूर करने के लिए बिना किसी राजनीतिक शर्त तथा दबाव के विशेष एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राज्यवादी अभिशाप से बचने के लिए विशेष एजेंसियों के माध्यम से ही हर तरह की सहायता प्राप्त करना न्यायोचित है। इस तरह की सेवा द्वारा यदि उन्नतिशील राष्ट्रों की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था ठीक हो मकी तो यह अवश्य ही इतिहास की युगपरिवर्तक घटना होगी।¹



वर्तमान विश्व की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ :

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका का जागरण,
महाशक्तियाँ और तृतीय विश्व
(Contemporary Emerging Trends :
Resurgence of Asia, Africa and Latin America,
Super Powers and the Third World)

“इन (एशियाई) पिछड़े हुए राष्ट्रों के नए बुद्धिजीवियों ने वित्तान, पुढ-कला तथा राजनीति में पश्चिमी राष्ट्रों की दक्षता और निपुणता का ज्योंही एक आंशिक भाग प्राप्त किया, त्योंही उनमें इस बात की मांग करने वाले नेतागण भी पैदा हो गए कि उन्हें अपना भविष्य स्वयं निश्चित करने का अधिकार मिलना चाहिए।” —शूर्मा

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका का जागरण द्वितीय महायुद्ध के बाद की एक सर्वोपरि महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी घटना है जो सारे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जगत् को विभिन्न रूपों में प्रभावित कर रही है। इन तीनों ही क्षेत्रों के अधिकांश राज्य साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी दासता के शिकवे में जकड़े हुए थे। पर समय ने करवट ली, दासता से मुक्त होने के लिए चल रहे संघर्षों की विजय हुई, नव-जागरण की लहर को साम्राज्यवादी शक्तियाँ दबा नहीं सकी और आज एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत-कुछ अपना स्वतन्त्र अस्तित्व धारण किए हुए हैं। जो भू-भाग आज भी उपनिवेशवाद के शिकार हैं, वे भी निकट भविष्य में मुक्त होकर रहेंगे। जो राज्य उपनिवेशवादी शक्तियों के प्रभाव में हैं, वे शीघ्र ही पूर्ण सार्वभौमिकता का उपभोग करके रहेंगे। शतान्तरियों से पिछड़े ये महाद्वीप अब जाग चुके हैं, भंगडाई ले रहे हैं और इनके बढ़ते कदमों को विश्व की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।

इसके पहले कि हम इन महाद्वीपों के जागरण पर विचार करें, यह उचित होगा कि पृष्ठभूमि के रूप में विश्व की परिस्थितियों में परिवर्तन के आघातों और विश्व-राजनीति पर प्रभाव डालने वाली प्रवृत्तियों को सांकेतिक रूप में समझ लें।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियाँ (Contemporary Emerging Trends)

वर्तमान विश्व के राजनीतिक परिवर्तनों का स्पष्ट चित्र खींचते हुए टी. वी. कालिजावी ने लिखा है, "वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का पुनर्गठन हो रहा है जिसमें पूर्ववर्ती राज्य-व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था धीरे-धीरे नवीन राजनीतिक रूपों में परिवर्तित हो रही है। साम्राज्यों का पतन हो रहा है और उपनिवेश स्वतन्त्रता प्राप्त करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राज्य एक बड़े संघ में विलीन होते जा रहे हैं।" जहाँ एक ओर पुनर्निर्माण और विकास के महान् प्रयत्न चल रहे हैं तो दूसरी ओर प्रलयकारी शास्त्रास्त्रों के रूप में महाविनाश की विपुल शक्ति भी मानव के हाथों में केन्द्रित हो चुकी है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय महायुद्धोत्तर तत्त्वों और आधुनिक उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों पर यत्र-तत्र प्रकाश डाला जा चुका है। तथापि उनका सामूहिक रूप में एक ही स्थल पर संकेत कर देना उपयोगी होगा। ये तत्त्व एवं प्रवृत्तियाँ मुख्यतः निम्नलिखित हैं—

1. राष्ट्रवाद—एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका राष्ट्रवाद की लहरो से उद्वेलित हैं। यद्यपि लेटिन अमेरिका के बहुत से देश अमेरिका के प्रभाव-क्षेत्र में हैं, तथापि क्यूबा की क्रान्ति ने राष्ट्रवाद की किरणों से सम्पूर्ण लेटिन अमेरिका को आलोकित कर दिया है। राष्ट्रवाद ने इन भू-भागों के विभिन्न राज्यों में अपनी स्वतन्त्रता, संस्कृति और परम्परा के लिए प्यार पैदा किया है पर जहाँ राष्ट्रवाद अपने रचनात्मक रूप में उभरा है वहाँ कतिपय क्षेत्रों में इसका विध्वंसात्मक रूप अराजकता और संघर्ष के विस्फोटक केन्द्रों के लिए भी उत्तरदायी है। अरब जगत् धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद और इस्लामी राष्ट्रवाद की जबरदस्त खींचावानी का केन्द्र बना हुआ है, तो पाकिस्तान का इस्लामी राष्ट्रवाद भारतीय उप-महाद्वीप को अशान्त बनाए हुए है।

2. हासोन्मुख राष्ट्रमण्डल—एक बहुजातीय (Multi-racial) सत्ता के रूप में जिस प्रभावशाली राष्ट्रमण्डलीय संगठन का उदय और विस्तार हुआ वह विगत कुछ वर्षों से शिथिल पड़ता जा रहा है। ब्रिटिश राजनीतिक और आर्थिक नीतियों ने, प्रजातीय असहिष्णुता ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कतिपय राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रमण्डलीय मंच के दुरुपयोग करने की नीति ने, नवपृथ्वीवाद ने और कुछ अन्य समस्याओं ने राष्ट्रमण्डल की बुनियाद को खोखला कर दिया है। रोडेशिया के प्रति ब्रिटेन की बुलमुन और परोक्ष रूप में पक्षपातपूर्ण नीति भी राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीकियाई देशों के विश्वास को डगमगाने वाली है। इसमें अनेक देश, जिनमें भारत भी है, राष्ट्रमण्डल की भावी उपयोगिता पर सन्देह करने लगे हैं।

3. अरात्मनिरूप का जयघोष—'आत्मनिरूप' के सिद्धान्त के बल पर अनेक पराधीन राष्ट्रों के स्वाधीनता आन्दोलनों को एक दृढ़ आधार प्राप्त हुआ है और

आज यह अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी समय की अपेक्षा अधिक सशक्त स्थान ग्रहण किए हुए है। दिसम्बर, 1971 में बंगलादेश का उदय इस सिद्धान्त के जयघोष और 'घरेलू उपनिवेशवाद' (Domestic Colonialism) पर करारा प्रहार है।

4 साम्यवाद और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया—रूसी और चीनी साम्यवादी विचारधारा एशिया और अफ्रीका में अपना विशेष प्रभाव जमा चुकी है। प्रतिक्रिया-स्वरूप पश्चिमी शक्तियाँ अपने प्रभाव की रक्षा के लिए तेजी से सन्नद्ध हुई हैं। इस प्रकार एशिया और अफ्रीका साम्यवादी और पूँजीवादी खेमों के विभिन्न सघर्षों का रंग-मंच बन गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्भवतः कोई भी क्षेत्र इन दोनों पक्षों की क्रिया-प्रक्रिया से बचा हुआ नहीं है। यह क्रिया-प्रक्रिया विशेषतः तीन रूपों में अधिक प्रभावशाली हुई है—

(क) पश्चिमी शक्ति और उनके साथियों द्वारा अनेक ऐसी संधियों और संगठनों का विकास किया गया है जिसका मुख्य लक्ष्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। इन सगठनों के जवाब में साम्यवादी पक्ष द्वारा वारमा पैक्ट आदि अन्य सुरक्षात्मक संगठन कायम किए गए हैं।

(ख) गरीब और हीन देशों की जनता अविलम्ब साम्यवाद की ओर आकर्षित होती है—यह समझ लेने के बाद पाश्चात्य शक्तियाँ सन्-विकसित देशों को हर प्रकार से सहायता देने लगी ताकि उनका जीवन-स्तर और मनोबल ऊँचा उठे। पश्चिमी शक्तियों के प्रयासों के जवाब में साम्यवादी शिविर भी एशिया और अफ्रीका के विछड़े राष्ट्रों की आर्थिक व सैनिक सहायता पर उतर आए हैं। इनमें रूस का स्थान सर्वोपरि है।

(ग) शीतयुद्ध और शस्त्रीकरण का प्रसार हुआ है, लेकिन साथ ही सह-अस्तित्व की विचारधारा भी पनपी है, विशेषकर इस अनुभूति के बाद कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नष्ट करने में सक्षम हैं और महायुद्ध का अर्थ होगा महाविनाश।

5 शीतयुद्ध—महाशक्तियों के सघर्ष ने 'शीतयुद्ध' के एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को जन्म दिया है। सौभाग्यवश सन् 1970 के बाद से इसकी तीव्रता में बहुत कमी आई है, तथापि मौके-बेमौके उग्र होकर इसने अनेक बार विश्व के समस्त प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में जो सम्भार राजनीतिक और सैनिक सत्तों खड़े किए हैं, उन्हें विश्व की शान्तिप्रिय जनता मुला नहीं सकती।

6. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व—यह विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुकी है। भारत जैसे असन्तुष्ट राष्ट्रों ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के विचार को सबसे अधिक विकसित किया है। सोवियत रूस में स्टालिन तथा स्टालिनवाद की समाप्ति के बाद जो नया उदारवाद धार्मिक रूप में उभरा है उसने असन्तुष्ट देशों के प्रति मैत्री प्रदर्शित की है तथा सह-अस्तित्व की

विचारधारा में विश्वास प्रकट किया है। चीन, पाकिस्तान भी अपने उग्रवादी दृष्टिकोण को बदल रहे प्रतीत होते हैं।

7. चीन-सोवियत सम्बन्धों में नए मोड़ के संकेत—रूस और चीन के बीच चलने वाले सिद्धान्तिक संघर्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। पहले साम्यवाद और लोकतन्त्र इन दो सिद्धान्तों का ही संघर्ष विश्व को दो शक्ति-गुटों में विभक्त किए हुए था, लेकिन अब साम्यवादी खेमे में ही दो बड़ी शक्तियों की विचारधारा में टककर होने लगी है। भूतभेद इतने बढ गए कि दोनों देशों की सीमाओं पर कई बार तेज सैनिक झड़पें भी हुईं और एक दूसरे पर आक्रमण की आशंका भी व्यक्त की गई। 12 सितम्बर, 1976 को माओत्से-तुंग की मृत्यु से पूर्व तक राजनीतिक क्षेत्रों में मुख्यतः यही विचार था कि दोनों देशों के सम्बन्ध निबट भविष्य में सम्भवतः सुधर नहीं सकेंगे। पर माओ की मृत्यु के बाद नए नेतृत्व के शासनकाल में चीन-सोवियत सम्बन्धों में नए मोड़ के संकेत मिले हैं।

8. अणु-स्वामित्व का प्रसार—अणु-शक्ति के विवास ने विश्व-राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। अब रूस और अमेरिका ही अणु शक्ति के स्वामी नहीं हैं, बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि राष्ट्र भी इस क्षेत्र में काफी आगे बढ चुके हैं। चीन जिस तेजी से अणु शक्ति का स्वामी बनता जा रहा है वह महाशक्तियों तक के लिए चिन्ता का विषय बन गया है और उनकी विदेश-नीतियाँ इस तथ्य से प्रभावित होने लगी हैं। भारत अपनी घोषित नीति के अनुरूप 'शान्ति के लिए' आणविक विस्फोट कर चुका है। भारत शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का समर्थक है तथापि कुछ पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति वह उदासीन नहीं रह सकता। भारत की विदेश-नीति का, सम्भावित खतरों को देखते हुए, पुनर्निर्धारण किया जा रहा है जिसका एक स्पष्ट प्रमाण भारत-सोवियत मैत्री-सन्धि है।

9. एशिया-अफ्रीका का जागरण तथा सम्प्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि—पिछले लगभग पच्चीस वर्षों से दोनों महाद्वीपों के पराधीन राष्ट्र एक-एक करके स्वतन्त्र होते गए हैं और आज सम्पूर्ण यूरोपीय साम्राज्यवादी अथवा औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तिम साँसें गिन रही है। जहाँ पहले सत्तार की जनगणना का लगभग 33% भाग साम्राज्यवाद के शिकारे में था, वहाँ यह अब 2% भी नहीं रहा है। सम्प्रभु राज्यों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि जहाँ सन् 1944 में संयुक्त-राष्ट्र के सदस्यों की संख्या केवल 51 थी, वहाँ आज यह 156 है। सम्प्रभु राज्यों की मर्यादा में अभूतपूर्व वृद्धि के फलस्वरूप विश्व-राजनीति का स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है और विभिन्न राज्यों के स्तरों तथा स्थितियों में तेजी से परिवर्तन आ रहा है।

10. महासागरीय प्रतिस्पर्धाएँ—हाल ही के कुछ वर्षों में भूमध्यसागर और हिन्दमहासागर महाशक्तियों की शक्ति-मंच के महत्वपूर्ण स्थल बन गए हैं। भूमध्यसागरीय क्षेत्र में महाशक्तियाँ अपनी नौ-सैनिक शक्ति के विस्तार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों में गन्तु बन आ रहे या बढाने में सैनिक और आर्थिक विचारों का योगदान इतना नहीं है जितना राजनीति का

11. **अफ्रीकीकरण की लहर**—पिछले कुछ वर्षों से अफ्रीका में 'अफ्रीकीकरण' की संकुचित नीति की लहर व्यापक रूप से फैली है। अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में, जिन्होंने कुछ ही समय पूर्व ब्रिटेन की अधीनता से मुक्ति प्राप्त की है, प्रवासी भारतीयों को वहाँ के उच्च जातीय राष्ट्रवाद अथवा प्रचंड अतिवाद के कारण अपमानित, उत्पीड़ित, उन्मूलित तथा देश से निष्कासित होना पड़ रहा है। ये प्रवासी भारतीय भारत-मूल के लोग हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि सभी के वंशज सम्मिलित हैं। परिस्थितियों का तकाजा है कि हमारी राष्ट्रीय नीति इस केन्द्र बिन्दु पर आधारित होनी चाहिए कि संसार के किसी भी क्षेत्र में भारतीयों को राष्ट्रहीनता के अभिशाप से अपमानित और पीड़ित नहीं होने दिया जाएगा।

12. **'कभी के राष्ट्र राज के मित्र' की बदलती प्रवृत्ति**—राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी शत्रु। जिस साम्यवादी चीन को अमेरिका अपना शत्रु नम्बर एक मानता रहा उसी के प्रति मैत्री के हाथ बड़ाकर भूतपूर्व राष्ट्रपति निसन ने अमेरिकी कूटनीति को एक पान्धिकारी मोड़ दिया। वर्तमान अमेरिकी विदेश-नीति का एक मुख्य लक्ष्य वाशिंगटन-पेकिंग-पिण्डो धुरी को सुदृढ़ करना प्रतीत होता है। सोवियत रूस के प्रति भी अमेरिकी रवैये में एक बड़ा अन्तर आया है। सोवियत रूस के साथ मैत्री और सहयोग की आकांक्षा से निसन ने सन् 1972 के मध्य मास्को की जो यात्रा की वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नए मोड़ की सूचक थी। कूटनीति की इन 'नई ब्यूह रचनाओं' के फलस्वरूप ही वियतनाम का ज्वालामुखी शान्त हो सका। ये कूटनीतिक प्रवृत्तियाँ इस बात का भी संकेत देती हैं कि महाशक्तियाँ वास्तव में दूसरों की खातिर एक दूसरे से उलझता नहीं चाहतीं। वाशिंगटन-पेकिंग-पिण्डो धुरी के मुकाबले शक्ति-सन्तुलन बनाए रखने, चीनी विस्तारवाद पर अकुश रखने और एशिया में एक शक्तिशाली देश को मित्र बनाए रखने की आकांक्षा ने ही सोवियत रूस को भारत के प्रति पूर्ण सक्रिय रूप में सहानुभूतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बनाया है। भारत भी सोवियत रूस की महान् मैत्री के मूल्य को समझता है।

13. **द्विध्रुवीयता से बहुकेन्द्रवाद की ओर**—अन्तर्राष्ट्रीय जगत् द्विध्रुवीयता (Bipolarity) से शनः-शनः बहुकेन्द्रवाद (Polycentrism) की ओर अग्रसर हो रहा है और आज स्थिति यह है कि विश्व में शक्ति के दो से अधिक केन्द्र स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुके हैं। एशिया में भारत और चीन नए शक्ति-केन्द्र हैं जो विश्व की शक्ति-सन्तुलन को किसी ओर भी मोड़ देने में सक्षम हैं। मध्यपूर्व में इजरायल भी वह शक्ति-केन्द्र बन चुका है जिसकी उपेक्षा करना भूल होगा। वर्तमान घासार यही है कि अभी अनेक महत्वपूर्ण शक्ति-केन्द्रों का उदय होना बाकी है।

14. **हिन्द-चीन नवनिर्माण की ओर**—सन्धे समय से युद्ध की ज्वालाओं में घबकता हिन्द-चीन का प्रदेश सन् 1973 के प्रारम्भिक चरण में शान्ति की ओर अग्रसर हुआ। सन् 1975 के भाते-भाते स्थिति पुनः विस्फोटक बन गई और वियतनाम तथा कम्बोडिया में युद्ध ने निर्णायक मोड़ ले लिया। पर युद्ध के साथ-

साथ शान्ति-वार्ताएँ भी बल पकड़ती गई और अन्ततः सन् 1975 के मध्य तक कम्बोडियायी तथा वियतनामी सघर्ष का अन्त हो गया और इस तरह विश्व ने महायुद्ध के एक सम्भावित खतरे से मुक्ति की साँस ली। युद्ध के बाद वियतनाम में नवनिर्माण और एकीकरण का दौर चला और आखिर 24 जून, 1976 को उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम एकता के सूत्र में बँध गए। हिन्द-चीन भयावह युद्ध की ज्वालाओं से मुक्त है लेकिन राज्यों से सीमान्त सघर्ष तो होते ही रहते हैं। वास्तव में जब तक आर्थिक पुनर्निर्माण का प्रश्न हल नहीं हो जाता, विस्फोटक परिस्थितियों के पुनः उत्पन्न होने की आशंका बनी रहेगी।

15. एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में प्रयत्न—हाल ही के वर्षों में राजनीतिक तनाव कम होने, उपनिवेशवाद खत्म होने तथा गुट-निरपेक्ष देशों की एकता मजबूत होने की दिशा में प्रगति के साथ ही विकासशील तथा विकसित देशों की एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सृजन के मार्ग में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी बराबर प्रयत्न होते रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत की भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण रही है। भारत का यह निश्चिन्त मन है कि विकासशील राष्ट्रों में सहयोग न सिर्फ वृहत्तर आत्मविश्वास के लिए अनिवार्य है वल्कि बड़े राष्ट्रों के उस दबाव का मुकाबला करने के लिए भी, जिसे वे विकासशील देशों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाने के लिए डाल रहे हैं ताकि विश्व के विभिन्न भागों में उनके अपने हित और अधिक विस्तृत हो सकें।

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में जागरण के कारण (Factors Responsible for the Resurgence of Asia, Africa and Latin America)

1. द्वितीय महायुद्ध ने विश्व-इतिहास के निर्माण यूरोप की आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से अपाहिज तथा 'समस्या प्रधान' (Problem Europe) बना दिया। जर्मनी और इटली विलुप्त हो गए तथा ब्रिटेन और फ्रान्स नीसर्गी थ्रेणी के राष्ट्र बन गए। इन राज्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि वे अपने विशाल साम्राज्य का भार सम्भाल सकें।

2. महायुद्ध में श्वेत जातियों को जो गहरे धक्के लगे उनसे अफे शियाई जनता के स्वाधीनता-घान्दोलन में नई जान आई। यकें हुए यूरोप के लिए इन घान्दोलनों को दबाना मुश्किल हो गया और एक के बाद एक एशियायी तथा अफ्रीकी राष्ट्र स्वतन्त्र होते गए।

3. मयुक्त-राज्य अमेरिका महायुद्ध के बाद सबसे शक्तिशाली पूँजीवादी राष्ट्र के रूप में प्रकट हुआ। उसने दोहरी नीति अपनाई—एक ओर तो दूटती हुई साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी व्यवस्था में नए प्राण फूँकने के लिए ब्रिटेन, फ्रान्स आदि को अपने मोहरे के रूप में प्रयोग करना चाहा और दूसरी ओर उभरते हुए एशियायी राष्ट्रों के मन में यह बात बँटानी चाही कि अमेरिका तो वास्तव में लोकतन्त्र का

पोपक और उपनिवेशवाद का विरोधी है। अमेरिका नहीं चाहता था कि समाजवादी तत्त्व एशिया के नवोदित राष्ट्रों को अपने प्रभाव में ले लें, अतः साम्राज्यवादी प्रकृति रखते हुए भी अमेरिका ने प्रारम्भ में अफ़ेशियायी जागरण का सुनकर विरोध नहीं किया बल्कि कोशिश यह की कि एशियायी जागरण को अपने हित में प्रयोग किया जाए। इस रीति का अन्ततोगत्वा परिणाम यह निकला कि अफ़ेशियायी राष्ट्रवाद शक्तिशाली हो गया और पश्चिमी राष्ट्र मुँह देखते रह गए।

4. अपार क्षति के बावजूद सोवियत रूस महापुद्ग के बाद एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व-रंगमंच पर आया और देखते-देखते यूरोप का लगभग सत्तस्त पूर्वी भाग साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत आ गया। इसमें साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद विरोधी शक्तियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला क्योंकि रूस सदा से ही राष्ट्रीय मुक्ति-प्रान्दोलनों का समर्थक रहा था।

5. पूंजीवादी और साम्यवादी शक्तियों ने एक दूसरे के प्रभाव-विस्तार को रोकने के लिए और एक दूसरे के घेराव के लिए अफ़ेशियायी राष्ट्रों को आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक मदद देना शुरू किया। दोनों ही पक्षों ने यह दिखाने की कोशिश की कि वे अफ़ेशियायी देशों के हितेषी हैं। इस प्रतिस्पर्धा का परिणाम यह निकला कि अफ़ेशियायी राष्ट्र अपने राजनीतिक और सामरिक महत्त्व को अधिक अच्छी तरह समझते लगे। एशिया-अफ़्रीका और लेटिन-अमेरिका का जागरण विश्व की महाशक्तियों की पारस्परिक विरोधी नीतियों के सन्दर्भ में धीमी गति से शुरू होकर तेजी से विश्व-राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गया।

6. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने विशेषकर संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए जिनसे अफ़ेशियायी और लेटिन अमेरिकी जागरण को बड़ा बल मिला। न्यास-परिषद् (Trusteeship Council) ने उपनिवेशों में सरक्षक राष्ट्रों पर सांविधानिक सुधार के लिए जोर डाला और एक निर्धारित समय में उन्हें स्वतन्त्र कराने का कार्यक्रम बनाया। कुछ वर्षों पूर्व न्यास-पद्धति के अन्तर्गत न्यूगिनी, रूमाण्डाउरुण्डी, फ़ॉच कैमरूनस, फ़ॉच टोगोलैण्ड, पश्चिमी समोआ, टोंगानिका ब्रिटिश कैमरूनस, नौरू, प्रशान्त महासागरीय द्वीप, सुमालीलैण्ड, टोगोलैण्ड नामक 11 देश थे। अब ये सभी स्वाधीन हो चुके हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब प्रादेशिक साम्राज्यवाद का इस घरती से पूरा लोप हो जाएगा। जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद में 'सूर्य कभी अस्त नहीं होना था' वह साम्राज्य अब केवल अपनी सीमाओं में सिमट कर रह गया है।

7. पाश्चात्य शक्तियों, विशेषकर अमेरिकी प्रभाव के बावजूद संयुक्त राष्ट्र-संघ ने पिछड़े हुए तथा औपनिवेशिक दासता से पीड़ित जनसमूहों की समस्याओं की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। विश्व-रंगमंच के माध्यम से अफ़ेशियायी तथा लेटिन-अमेरिकी देशों में स्वातंत्र्य भावनाओं को बल मिला।

8. द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएँ कुछ यूरोपीय राष्ट्रों का ही ममाला न रहकर विश्व-व्यापी समस्याएँ बन गईं जिनके प्रति कोई भी देश उदासीन नहीं रह सकता। इसी प्रकार शक्ति का केन्द्र यूरोप न रहकर अमेरिका और हम हो गए तथा विश्व इन दोनों महाशक्तियों के प्रभावों के अन्तर्गत व्यवस्थित हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसार और शक्ति के प्रवृत्तिकरण, इन दोनों पहलुओं का एशिया और अफ्रीका के जागरण पर व्यापक प्रभाव पड़ा और आज भी पड़ रहा है।

9 आवागमन तथा संचार के वैज्ञानिक साधनों के फलस्वरूप दुनिया ज़िम् नरह मिकुडकर छोटी हो गई है, उसमें भी यह स्वाभाविक है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन-अमेरिका आदि वे देश समझ गए कि वे यूरोपीय राष्ट्रों तथा अमेरिका से आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से कितने पिछड़े हुए हैं। यह अनुभूति इन भू-क्षेत्रों के जागरण का एक मुख्य कारण बनी। इन महाद्वीपों के राष्ट्रों में यह ग्राम धारणा व्याप्त है कि पश्चिमी राष्ट्र ही उनके पिछड़ेपन और शोषण के लिए जिम्मेदार हैं और अब उन्हें स्वावलम्बी बनना है ताकि वे पुनः साम्राज्यवादी शिकजे में न फँस सकें।

10 साम्यवाद और पूँजीवाद की सैद्धान्तिक मान्यताओं के टकराव ने भी अर्कशियायी राष्ट्रों को इस ढंग से प्रभावित किया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं को सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में देख सकें। इन महाद्वीपों के विभिन्न राष्ट्रों की गृह और विदेश नीतियाँ साम्यवादी पूँजीवादी सिद्धान्तों के प्रभाव में अछूती नहीं हैं।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन-अमेरिका का जागरण वस्तुतः उस उभरते हुए राष्ट्रवाद का ही दूसरा नाम है जो इन महाद्वीपों के छोटे-बड़े राष्ट्रों की विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों और मान्यताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना-चक्रों और विशेषताओं के बीच टकराव तथा आदान-प्रदान के फलस्वरूप विकसित हुआ है।

एशिया का जागरण (Resurgence of Asia)

एशिया, पूर्व में प्रशान्त महासागर से पश्चिम में भूमध्यसागर तक तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में हिन्दमहासागर के मध्य स्थित दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या अपने में समेटे हुए यह महाद्वीप सभी प्रकार के धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं का घर है। यह महाद्वीप प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के बावजूद अधिक रूप से पिछड़ा हुआ है और राजनीतिक विकास की दृष्टि से भी बहुत पीछे है। यहाँ साम्यवाद और परम्परावाद साथ-साथ निवास करते हैं।

विभिन्न आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों तथा प्रभावों के आधार पर हम एशिया के जागरण को कुछ निश्चित युगों में बाँट सकते हैं—

- (1) प्रारम्भ से 1947 तक,
- (2) 1947 से 1955 तक,
- (3) 1955 से 1962 तक, एवं
- (4) 1962 से अब तक ।

प्रथम युग (प्रारम्भ से 1947 तक)

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में जब यूरोप तदाकथित 'प्रौद्योगिक भ्रान्ति' के प्रभाव से मध्यकालीन अवस्था का परित्याग कर आधुनिक अवस्था में पहुँच रहा था उस समय एशिया ने अपनी अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं राजनीतिक संगठन सम्बन्धी प्राचीन परम्पराओं का परित्याग करने से इन्कार कर दिया । परिणाम यह निकला कि यूरोप प्रगति करता गया और एशिया पिछड़ता चला गया । इतना ही नहीं, 'पश्चिम' ने एशिया को पराजित कर उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया ।

शनैः-शनैः जापान, थाईलैण्ड, ईरान, नेपाल और चीन को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण एशिया पाश्चात्य राष्ट्रों के अधीन हो गया । अंग्रेज भारत, बर्मा, श्रीलंका, मलाया, सिंगापुर और हांगकांग में जम गए, फ्रांसीसियों ने हिन्द-चीन में डेरा जमा लिया, डचों ने ईस्ट इण्डोस में पैर रोप दिया, रूसियों ने चीन के आसन्न प्रान्त सहित साइबेरिया या बाह्य मंगोलिया में और स्पेनिश लोगों के (बाद में अमेरिकियों ने) फिलीपाइन में अपने बड़े स्थापित कर लिए, यहाँ तक कि पुर्तगाल जैसे छोटे से राज्य ने भी अपने उपनिवेश कायम कर लिए । वे देश भी, जो देखने में स्वतन्त्र थे, व्यावहारिक दृष्टि से विदेशी राष्ट्रों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके ।

एशिया में स्वतन्त्रता आन्दोलनों का सूत्रपात—एशिया के राष्ट्र पहले से ही आर्थिक दृष्टि से अविवर्धित व्यवस्था में थे । पाश्चात्य शक्तियों ने उन पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद उनके आर्थिक शोषण की नीति अपनाई । यह आर्थिक शोषण क्रमशः इतना भयानक हो गया कि एशिया के अनेक समृद्ध राज्यों को भी भुखमरी, पीड़ा और नाना कष्टों का शिकार होना पड़ा । शनैः-शनैः एशियावासी समझ गए कि उनकी इन सब कठिनाइयों का निराकरण तभी सम्भव हो सकेगा जब वे विदेशी शासन से मुक्ति पा जाएँगे । इस प्रकार की चेतना बहुत कुछ पश्चिमी ज्ञान, साहित्य, कानूनों और सत्त्वामों के कारण पैदा हुई । पूर्व को 'पश्चिम' के राष्ट्रवादी विचारों और उसके उच्च जीवन स्तर ने सर्वाधिक प्रभावित किया ।

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर एशिया और अफ्रीका में स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र की पहली लहर आई । एशियावासी 'आत्म-निर्णय' की माँग करने लगे । 'भारत भारतीयों के लिए', 'चीन चीनियों के लिए' आदि आवाजें बुलन्द होने लगी । सम्पूर्ण महाद्वीप में पाश्चात्य प्रभुत्व से छुटकारा पाने की जो प्रबल लालसा जाग्रत हुई उसने एक लम्बे स्वतन्त्रता आन्दोलन और संघर्ष का रूप धारण कर लिया । एशिया के लगभग सभी पराधीन राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति

पर क्रान्तिकारी पुनर्विचार की माँग करने लगे। एशिया तेजी से नव-जागरण के मार्ग पर अग्रसर हुआ। द्वितीय महायुद्ध ने एशिया महाद्वीप को अपना उद्देश्य प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया लेकिन सन् 1945 में पश्चिमी शक्तियों की विजय के बाद साम्राज्यवाद की पुरानी व्यवस्था पुनः ज्यों की त्यों स्थापित रह गई।

पर अब यह स्थिति अधिक समय तक जारी रहने वाली नहीं थी। द्वितीय महायुद्ध में श्वेत जातियों को जिन प्रारम्भिक गम्भीर पराजयों का सामना करना पड़ा था उससे एशियायी जनता को यह विश्वास हो गया कि पश्चिमी राष्ट्र अथवा 'गोरी चमड़ी' अजेय नहीं है। इस अनुभूति के फलस्वरूप स्वातन्त्र्य आन्दोलनों में नई जान आ गई। थके हुए यूरोप के लिए आजादी की लहर को दबाना मुश्किल हो गया और एक के बाद एक लगभग सभी एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों के स्वप्न पूरे होते चले गए। यह कहना सर्वथा उपयुक्त होगा कि सन् 1919 के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में साम्राज्यवाद की पराजय प्रारम्भ हुई और सन् 1945 के बाद इसका पूर्ण उन्मूलन होने लगा।

द्वितीय युग (1947 से 1955 तक)

इस अवधि में एशिया के जागरण ने नई करवट ली और एशियायी व्यक्तित्व का विकास हुआ। इस युग की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी—

स्वातन्त्रता की लहर का प्रसार तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में तीव्रता— विभिन्न एशियायी राष्ट्रों में स्वातन्त्रता-आन्दोलनों ने जोर पकड़ा और सन् 1947 में स्वतन्त्र भारत के उदय से एशियायी राष्ट्रवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला। बर्मा, श्रीलंका, कम्बोडिया, लाओस आदि अनेक राष्ट्र स्वतन्त्र हो गए। सोवियत रूस साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक महान् शक्ति के रूप में प्रकट हुआ, पुरानी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियाँ कमजोर पड़ती गईं इससे एशियायी राष्ट्रवादी शक्तियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। अनेक देशों में विकास-योजनाएँ प्रारम्भ हुईं और भारत ने गुटनिर्पेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। एशियायी एकता के स्वप्न को चरितार्थ करने के लिए स्व. श्री नेहरू ने दिल्ली में एशियायी सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें डच साम्राज्यवाद की भर्त्सना की गई और समुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया गया कि वह इण्डोनेशिया की स्वातन्त्रता की रक्षा करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। वास्तव में एशियायी एकता का यह पहला प्रदर्शन था जिसके फलस्वरूप इण्डोनेशिया में डच साम्राज्यवादियों के कुत्सित मसूचे पूरे नहीं हो सके।

चीन की साम्यवादी क्रान्ति—चीन में सन् 1949 में जो साम्यवादी क्रान्ति हुई वह भी एशियायी जागरण का प्रतीक थी। इस देश में साम्यवाद की स्थापना का एशियायी देशों की आन्तरिक और विदेश-नीतियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। एशिया के विभिन्न देशों की जनता कोरी राजनीतिक स्वातन्त्रता में सन्तुष्ट नहीं हुई और चीनी जन-क्रान्ति से प्रेरित होकर अब वह आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अधिक प्रयत्न करने लगीं अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आ गईं। जनता की आर्थिक और सामाजिक सुधार सम्बन्धी

मार्गों के प्रति विभिन्न एशियायी देशों में अलग-अलग नीतियाँ अपनाई गईं। कुछ देशों में जन-प्रान्दोलनों को कुचलने तथा स्वयं को सत्तारूढ़ करने के लिए नेताओं ने विदेशी सहायता का सहारा लिया। विदेशी शक्तियों ने सहायता की झाड़ में अपने हितों की सिद्धि करने की कूटनीति खेती और कनिष्ठ एशियायी देशों को अपनी सैनिक-सन्धियों के जाल में फँसाया। कुछ देशों में, आपिक विकास की माँग के सन्दर्भ में, सैनिक-शान्तियाँ भी हुईं। इन देशों ने साम्राज्यवाद विरोधी नीतियाँ अपनाई और सैनिक गुटों का विरोध किया। मिस्र आदि देश एशियायी एकता के समर्थक बने। सोवियत संघ ने इन देशों को समर्थन प्रदान किया। कुछ एशियायी देशों में साम्राज्यवादियों ने कमजोर नेताओं को टूटकर सत्ता ऐसे सैनिक अधिकारियों के हाथों में दे दी जो उनकी साम्यवाद-विरोधी योजनाओं में साथ देने को सहमत थे। थाईलैण्ड तथा पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ। जिन देशों में सत्ता सुधारवादी-शान्तिकारी नेताओं के हाथ में थी, जैसे भारत में, वहाँ व्यापक स्तर पर योजनाबद्ध तरीकों से विकास करने की नीति अपनाई गई। भारत जैसे देशों ने साम्यवाद का विकल्प सैनिक तानाशाही में नहीं अपितु समाजवाद, लोकतन्त्रवाद और धर्म-निरपेक्षता में देखा। साम्राज्यवादियों ने इन देशों की नीति पर अवसरवादिता का पल्ल आरोप लगाया पर सोवियत संघ ने आर्थिक सहायता और राजनीतिक समर्थन देकर इन देशों की लोकतान्त्रिक परम्पराओं और आर्मांशाओं को दृढ़ता प्रदान की।

सत्तारूढ़ नेतृत्व की प्रकृति के आधार पर एशियायी राष्ट्रों में मुख्य रूप से चार तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएँ कायम हुईं। छद्मवादी नेतृत्व वाले देशों में सैनिक तानाशाही अथवा विदेशी सरक्षण में दुर्बल राजनीतिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएँ बनी रही। सुधारवादी-शान्तिकारी नेतृत्व वाले देशों में उदारवादी प्रजातन्त्र या क्रान्तिकारी प्रजातन्त्र या साम्यवादी व्यवस्थाएँ कायम हुईं। देश की राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ही विदेश-नीति भी प्रतिपादित की जाने लगी।

एशियायी व्यक्तित्व का विकास (घाण्डुंग सम्मेलन)—विघटनकारी शक्तियों और बड़े राष्ट्रों के गुटीय संधियों से उत्पन्न खतरनाक परिस्थितियों के फलस्वरूप एशियायी देशों में एक प्रकार के सामूहिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और उनमें यह भावना जगी कि अपनी कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए उन्हें पारस्परिक एकता, संगठन और सहयोग का परिचय देना होगा।

इस प्रकार की एकात्मकता की नवीन चेतना की अभिव्यक्ति मार्च, 1947 में 'विश्व मामलों की भारतीय परिषद्' (Indian Council of World Affairs) के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित एक गैर-सरकारी 'एशियायी मैत्री सम्मेलन' (Asian Relations Conference) में हुई। इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुए और अनेक निर्णय लिए गए तथा 'एशियायी मैत्री संगठन' (Asian Relations Organisation) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई—

- (1) एशियायी समस्याओं और सम्बन्धों से सम्बन्धित महाद्वीपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं के अध्ययन और ज्ञान को प्रोत्साहित करना,

- (ii) एशियायी राष्ट्रों तथा विश्व के दूसरे राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना, एवं
- (iii) एशियायी जनता की प्रगति और हितों में वृद्धि करना ।

जनवरी, 1949 में 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने औपनिवेशिक विषयों पर विचार करने लिए एक अन्य सम्मेलन आयोजित किया । इस सम्मेलन में मुख्यतः इण्डोनेशिया में डच सरकार द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया गया । मई, 1950 में फिलीपाइन्स द्वारा बोर्नो नामक स्थान पर एशियावासियों के सांस्कृतिक व आर्थिक सहयोग पर विचार करने के लिए सम्मेलन आमन्त्रित किया गया । अप्रैल, 1954 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और इण्डोनेशिया के प्रधान मंत्री हिन्द-चीन सहित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए परस्पर मिले । दिसम्बर, में पाँचों प्रधान मंत्री बोगार में एकत्र हुए और वहाँ एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों का एक बृहद् सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में नव-जागरण की लहर का सर्वोत्तम रूप बाण्डुंग सम्मेलन में प्रकट हुआ । भारत, बर्मा और इण्डोनेशिया द्वारा इस महान् अफ्रीका-एशियायी सम्मेलन का आयोजन किया गया जो 18 अप्रैल, 1955 से 27 अप्रैल, 1955 तक चला । इस सम्मेलन में भारत सहित 29 राष्ट्र सम्मिलित हुए । पहली बार साम्यवादी चीन भी गैर साम्यवादी राष्ट्रों के साथ सद्भावना और मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए उपस्थित हुआ । सम्मेलन की समाप्ति पर सम्पूर्ण संसार को विश्वास हो गया कि सोया हुआ एशिया और अफ्रीका अब जाग उठा है । इस सम्मेलन में पण्डित नेहरू का शान्ति-सन्देश नए उरसाह के साथ सुना गया ।

बाण्डुंग सम्मेलन में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया कि स्वतन्त्रता का वास्तविक अन्तिम क्या है । काफी विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वास्तविक स्वतन्त्रता तभी कही जा सकती है जब उसमें निम्नलिखित तत्त्वों का समावेश हो—

- (i) विदेशी प्रभाव से मुक्ति एवं पूर्ण लोकतन्त्रात्मक स्वशासन,
- (ii) जाति, समुदाय और रंग सम्बन्धी किसी प्रकार के भेदभाव के बिना मानव-प्रतिष्ठा की मान्यता,
- (iii) तीव्र आर्थिक समृद्धि जिसका लाभ अधिकाधिक जनता को सुलभ हो, एवं
- (iv) युद्ध का उन्मूलन तथा सद्भावना का प्रसार ।

बाण्डुंग सम्मेलन में उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध किया गया । श्रीलंका के प्रधान मंत्री जॉन कोटलेवाना का मन था कि उपनिवेशवाद में साम्यवादी शासन के उस रूप को भी शामिल किया जाना चाहिए जो शक्ति और विध्वंस द्वारा स्थापित किया जाता है । काफी विवाद के बाद सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जनता की इच्छा के विरुद्ध शक्ति और विध्वंस द्वारा स्थापित शासन भी उपनिवेशवाद

है। बाण्डुंग सम्मेलन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक व्यवहार के दस सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिनमें से पाँच सिद्धान्त 'पञ्चशील' के थे। चार्लेट के शब्दों में, बाण्डुंग सम्मेलन, "एशिया और अफ्रीका के पुनरुत्थान का प्रतीक था। यह इस बात का ज्वलन्त उदाहरण था कि विश्व के मामलों में अब एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ रहा है।"

तृतीय युग (1955 से 1962 तक)

इस युग में एशियायी जागरण की सकारात्मक उपलब्धियों के नाम ही इसे कुछ नकारात्मक तथ्य भी सामने आए।

सकारात्मक पक्ष—कुछ समय तक 'बाण्डुंग भावना' का बोलबाला रहा। मतभेदों के बावजूद एशियायी देशों में सहयोग और मंत्री-भाव की प्रधानता रहने से संयुक्त राष्ट्रसंघ में अफ्रो-एशियायी गुट अस्तित्व में आया। ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्व के इन दो महाद्वीपों के छोटे-बड़े राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्राज्यवाद के विरुद्ध कन्धे से कन्धा भिड़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। अफ्रीकी-एशियायी गुट ने विश्व-संस्था के रंग-मंच पर उपनिवेशवाद और रंग-भेद की नीतियों के विरोध में सराहनीय ढंग से एकमत होकर कार्य किया। गुटनिरपेक्ष देश अमेरिका और रूस के बीच कटुता की खाई को थोड़ा बहुत पाटने में भी सफल हुए। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि दोनों महाशक्तियों के शीर्षस्थ नेताओं की मेंट हुई और विभिन्न विषयों पर दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की सद्भावना दिखाई। गुटनिरपेक्षता की ही यह देन थी कि एशियायी राष्ट्रों को विश्व-राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस अवधि में एशिया के और भी कई देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। वास्तव में एशियायी जागरण इस स्थिति में पहुँच गया कि विश्व की महाशक्तियाँ इस महाद्वीप के और अफ्रीका के राष्ट्रों की अवहेलना नहीं कर सकती थी।

नकारात्मक पक्ष : बाण्डुंग भावना की समाप्ति—बाण्डुंग सम्मेलन में एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रों के आपसी प्रेम और सहयोग के जो भाव विकसित हुए, वे दुर्भाग्यवश शीघ्र ही दब गए। साम्यवादी चीन ने सम्मेलन में अत्यधिक उदारतावाद का परिचय दिया, लेकिन यह उसकी गहरी कूटनीतिक भेडियाचाल थी। चीन एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों को अपनी भेडिया-चाल से बेसबर रख कर एशिया और अफ्रीका का नेतृत्व अपने हाथों में लेने का स्वप्न देख रहा था। बाण्डुंग सम्मेलन के कुछ ही दिनों बाद साम्यवादी चीन ने बाण्डुंग के 10 सिद्धान्तों का खुला उल्लंघन कर भारत की भूमि पर अपनी कु-दृष्टि डालना शुरू कर दिया और अन्य देशों पर भी अपना प्रभाव फैलाने का प्रयत्न करने लगा। इसके बाद ही 1962 में चीन ने भारत के साथ खुला संपर्क छेड़ दिया और आज भी दोनों राष्ट्रों के बीच सीमा-विवाद नायम है और चीनी नीति भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को उकसाते रहने की है।

सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य राष्ट्रों में भी राष्ट्रीय भावना की उग्रता,

राष्ट्रीय हितों की विभिन्नता और विघटनकारी तत्त्वों की प्रबलता के कारण बाण्डुंग भावना जैसी कोई चीज एशिया-प्रशान्त के राष्ट्रों में दिखाई नहीं देती। वास्तव में यह एशिया का दुर्भाग्य है कि आज एशियायी ऐक्य में काफी चौड़ी दरारें पड़ चुकी हैं।

चतुर्थ युग (1962 से मार्च 1982)

इस अवधि में एशियायी एकता को गहरे झटके लगते रहे हैं। भारत पर चीनी आक्रमण, क्यूबा पर अमेरिकी दबाव और रूस का सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना आदि घटनाओं ने अफ़ेशियाई देशों तथा लेटिन अमेरिकी राज्यों के सामने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें न केवल साम्राज्यवादियों और गैर-साम्राज्यवादियों के बीच चुनाव करना है बल्कि चीन की विस्तारवादी आकांक्षाओं और रूस-चीन-संघर्ष के सन्दर्भ में भी अपनी नीति निर्धारित करनी है। एशियायी एकता का स्वप्न अभी अमूर्त है—विघट बाधाएँ मार्ग में हैं। चीन और पाकिस्तान का गठबन्धन भारत के विरुद्ध मजबूती लेता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति को अधिकाधिक बढ़ाकर भारत को खतरा पैदा कर रहा है—इस उपमहाद्वीप के शक्ति-सन्तुलन को बिगाड़ रहा है। ईरान और ईराक परस्पर युद्ध-रत हैं तथा अन्य अरब देश भी आपसी फूट के शिकार हैं। बंगलादेश का रणैवा भी रचनाकूल नहीं है। फिर भी, आपसी वार्ताओं के दो दौर चल रहे हैं, वे निराला में आशा का सकेत दे रहे हैं।

स्पष्ट है कि एशिया जाग रहा है, राजनीतिक स्वाधीनता की लक्ष्य-प्राप्ति के उपरान्त अब उसके बरण आर्थिक स्वाधीनता की लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। एशिया में लोकतान्त्रिक शक्तियाँ प्रबल हो रही हैं। एशिया हर प्रकार के ओपण से मुक्त होने को छटपटा रहा है फिर भी एशियायी एकता की कल्पना अभी तक साकार नहीं हो सकी है। भारत, चीन और पाकिस्तान मिलकर एशियायी एकता की इमारत को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान जिस रास्ते पर अब तक चलते रहे हैं वह एशियायी एकता की जड़ खोद देने वाला है। फरवरी, 1982 में दिल्ली में भारत-पाक अनाक्रमण सन्धि की दिशा में जो विचार-विमर्ग हुआ वह उत्साहवर्धक है। यदि दोनों देशों के बीच अनाक्रमण सन्धि हो जाती है और पाकिस्तान ईमानदारी से उस पर अमल करता है तो यह बात एशियायी एकता को ठोस रूप में आगे बढ़ाने में सहायक होगी।

एशियायी राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

एशिया महाद्वीप की उपर्युक्त राजनीतिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से यहाँ अनेक प्रवृत्तियों और दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है। एशिया में अन्तिम अभी तक चल रही है। पहले इमका विरोध केवल विदेशी साम्राज्यवाद के प्रति था, पर आगे यह विरोध पुराने विचारों, अन्ध-विश्वासों, अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी और विविध सामाजिक बुराइयों के प्रति मनुष्यनिष्ठ किया जा रहा है। एशिया की जाति के कुछ निश्चिन्त परिणाम निकले हैं जिनमें राजनीतिक और सामाजिक अज्ञान, राष्ट्रीयता का विकास तथा साम्यवाद का प्रसार

प्रमुख हैं। सर्वत्र नई राजनीतिक और आर्थिक नीतियों तथा नई संस्थाओं का तेजी से विकास हो रहा है और स्पेण्डर के शब्दों में, "यह विकास राष्ट्रीय विचार की प्रेरक शक्ति के रूप में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार की भाँप के कारण भविष्य में जारी रहेगा।" एशिया के सभी देशों में राष्ट्रीयता की प्रबल लहर ने इजरायल से लेकर फिलिपाइन्स तक कई नए राष्ट्रों का निर्माण किया है। एशियायी राष्ट्रवाद पश्चिमी राष्ट्रवाद से भिन्न है। यहाँ के राष्ट्रवाद में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शान्ति, राजनीति के साथ-साथ परम्परावाद से प्रेम आदि का विविध सम्मिश्रण है। एशिया महाद्वीप में साम्राज्यवाद का अन्त हो रहा है, लेकिन साम्राज्यवादी मनोवृत्ति समाप्त नहीं हुई है और इसीलिए अनेक देशों में साम्यवाद के प्रति आकर्षण बहुत बड़ा है। सोवियत और चीनी साम्यवाद विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। एशिया के लगभग सभी देश आर्थिक और सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता के आकांक्षी हैं, लेकिन वे बड़ी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। बड़ी शक्तियाँ भी एशियावासियों और एशियायी नेताओं के दृष्टिकोणों की उपेक्षा नहीं कर पाती। एक शुभ-प्रभाव यह प्रकट हुआ है कि गुटों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी एशिया के अधिकांश देशों का मत है कि साम्यवादी व्यवस्था तथा पूँजीवादी प्रजातन्त्रों के बीच का एक रास्ता है जिसे आर्थिक दृष्टि से मिश्रित अर्थव्यवस्था और विदेश-नीति या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि में गुटनिरपेक्षता की नीति (Policy of Non-Alignment) कहा जाता है।

पामर और पकिंस (Palmer and Perkins) ने एशिया के प्रमुख देशों के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को पाँच भागों में विभाजित किया है—

- (1) साम्यवादी चीन का दृष्टिकोण,
- (2) राष्ट्रवादी चीन तथा कोरिया का दृष्टिकोण,
- (3) पश्चिम-समर्थक दृष्टिकोण,
- (4) ईरान-अरब-दृष्टिकोण, एवं
- (5) गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का दृष्टिकोण।

पामर और पकिंस का विभाजन उपर्युक्त है तथापि इसे तीन मुख्य भागों तक सीमित करना ही पर्याप्त होगा—साम्यवाद समर्थक दृष्टिकोण, पूँजीवाद समर्थक दृष्टिकोण और गुटनिरपेक्षता का दृष्टिकोण।

साम्यवाद का प्रभाव एशिया में बढ़ रहा है। एशिया का ही नहीं विश्व का महान्तम राष्ट्र चीन पूरी तरह लाल बन चुका है और अफ़ेजियायी देशों में अपना मानक फैलाने की प्रयत्नशील है। चीन चाहता है कि एशिया और अफ्रीका के देश उसका प्रमुख स्वीकार कर लें और उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चल कर साम्यवाद की स्थापना कर लें। इस दिशा में उसकी टक्कर सोवियत साम्यवाद से है जो एशिया में अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए पूर्ण रूप से सचेष्ट है पर दोनों देशों के रक्त और उनकी रीति-नीति में अन्तर है। साम्यवादी चीन विस्मरणवाद और भातृकवाद का प्रतीक सिद्ध हुआ है जिससे एशिया और अफ्रीका के छोटे-मोटे

अधिकांश राष्ट्र आशंकित हो गए हैं। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी देश चीन के जिकजे में ब्यासम्भव नहीं फँसना चाहते। पाकिस्तान अपनी भारत-विरोधी नीति के कारण चीन की आर्थिक और सामरिक सहायता पर अधिकाधिक आश्रित होता जा रहा है। उसने मार्च, 1953 में 'सिकिमांग और कश्मीर-सीमा विषयक अन्तिम समझौते' के अन्तर्गत अवैध रूप से हड़पी हुई भारत की भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा चीन को सौंपकर माओ की कृपा अर्जित की है। भारत पर चीन के अकारण दारुणता के बाद एक ओर तो अफ़े शियायी राष्ट्र चीनी विस्तारवाद की ओर से चौकन्ने हो गए हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान चीन को साम्यवाद के प्रसार के लिए प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में आमन्त्रित करता रहा है—एशिया महाद्वीप इस विचित्र विरोधाभास में त्रस्त है। सन् 1976 में राजदूतों के आदान-प्रदान के बाद से भारत और पाकिस्तान तथा भारत और चीन के सम्बन्धों में जो नया मोड़ लिया है, वह यदि वास्तव में रचनात्मक रूप लेना है तो इस महाद्वीप की कायापालट होने में देर नहीं लगेगी।

साम्यवाद एशिया पर न छा जाए, इसलिए पश्चिमी शक्तियाँ एशिया के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सचेष्ट हैं। पाकिस्तान, इजरायल, ईरान, टर्की आदि राष्ट्र अमेरिका और उसके सहियों के प्रभाव-क्षेत्र हैं। नाटो, सीटो, सेंटो सन्धि-वगैरों द्वारा इस भू-भाग के कतिपय राष्ट्र साम्यवाद-विरोध के नाम पर अपनी सैनिक शक्ति को प्रबल बना रहे हैं। जापान भी अमेरिकी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है, यद्यपि जापानियों की आकांक्षा पूर्णतः 'स्वतन्त्र' दृष्टिकोण अपनाने की है।

एशिया महाद्वीप गुटनिर्पेक्षता के दृष्टिकोण ने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। यहाँ के अनेक देश इस नीति में विश्वास करते हैं जिनमें भारत का स्थान सर्वोपरि है। कोलम्बो शक्तियों में सबसे अधिक प्रभावशाली यह देश अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक और सैनिक स्थिति के कारण प्रभावपूर्ण रूप से अपनी आवाज बुलंद करने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में और अन्यत्र भारतीय नेताओं ने सदा ही एशिया की एकता के लिए कार्य किया है। एशिया और अफ्रीका में गुटनिर्पेक्ष विदेश-नीति के समर्थक राष्ट्र विश्व के पूँजीवादी और साम्यवादी पक्षों में सन्तुलनकारी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये राष्ट्र अपने आपको किसी 'वाद' के साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहते, तथापि यह स्पष्ट है कि वे संयुक्त रूप में विश्व की एक तीसरी महाशक्ति सिद्ध हो सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भावना के दृष्टिकोण और आदर्श, पामर एवं पश्कित के अनुसार ये हैं—(1) जातीय भेद-भाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध, (2) साम्यवाद अथवा शक्ति-राजनीति की अपेक्षा राष्ट्रों के आधारभूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर बल, (3) एशियायी देशों की उपेक्षा न करने और उन पर बलान्त्रु जुड़ न घोंपने पर आग्रह, (4) स्वतन्त्रता अथवा गुटनिर्पेक्षता की नीति पर बल, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयोग

में विश्वास, (5) जीतयुद्ध एवं क्षेत्रीय सुरक्षा-संगठनों से पृथक्ता, तथा (6) अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने वाले और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ाने वाले प्रयत्नों में आस्था।

महाशक्तियाँ और एशिया (Super Powers and Asia)

यह देखना रोचक होगा कि महाशक्तियाँ ने एशियायी देशों के मामलों में कितनी रुचि दिखाई है, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या-क्या गुल खिलाए हैं, शक्ति-सन्तुलन की राजनीति का क्या खेल खेला है, वहाँ-कहाँ कैसे और क्यों अपनी 'राजनीतिक पाटियाँ' स्थापित की हैं, किन नए क्षेत्रीय संगठनों को जन्म दिया है, कहीं कैंसा लज्जास्पद नाटक खेला है और कई बार 'उलटी चपन' खाई है, किस प्रकार का कूटनीतिक मनोवैज्ञानिक तथा सैनिक युद्ध जारी रखा है, गिरगिट की तरह रंग बदलकर कैसे कभी तो घमती और बन्दर-भभकी दिखाई है और कैसे कभी 'अपना मुँह काला होने' का अपयश घोषा है? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से यह सारा घटना-चक्र अध्ययन की महत्त्वपूर्ण सामग्री है।

पिछले एक दशक में सोवियत संघ अमेरिका और चीन ने एशियायी देशों के मामलों में जितनी रुचि दिखाई उनकी शायद पहले कभी नहीं दिखाई थी। पश्चिमेशिया हो या हिन्दमहासागर अथवा दक्षिणपूर्वी एशिया सर्वत्र ये महाशक्तियाँ घरनी-घरनी गोठियाँ बिठाने में व्यस्त हैं जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि एशिया में कोई न कोई मोर्चा बना रहता है।

महाशक्तियाँ जहाँ एक ओर परस्पर समझौते का प्रयास करती हैं, दूसरी ओर अपने प्रभाव-विस्तार की होड़ में वे एशियाई देशों को शस्त्रास्त्रों से सज्जित भी करती हैं। अमेरिका ने न केवल हिन्द-चीन के देशों को बेगुमार सैनिक-आर्थिक सहायता दे कर वहाँ स्थायी प्रशान्ति की स्थिति पैदा की बल्कि भारतीय उप-महाद्वीप में भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965 और 1971 में हुई तीन कड़ी लड़ाइयों के लिए भी मूलतः वही जिम्मेदार रहा। पश्चिमी एशिया में जून, 1967 में अरब-इजरायल युद्ध और उसके बाद की सतत शान्ति के लिए भी राजनीतिक क्षेत्रों में मूलतः उसे ही उत्तरदायी माना जाता है, वैसे स्थिति को उलझाने में सोवियत संघ और चीन का भी हाथ रहा। पर्व के पीछे महाशक्तियों की सहमति के फलस्वरूप ही पश्चिम एशिया अब शान्ति की ओर अग्रसर है।

हिन्दमहासागर इन बड़ी शक्तियों की शक्ति-सन्तुलन की राजनीति का ताजा केन्द्र है। हिन्दमहासागर कभी किसी भी देश की नीतिना के लिए बजित जलक्षेत्र नहीं रहा, परन्तु हाल के कुछ वर्षों में अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने इस जल-क्षेत्र में जो विशेष रुचि दिखाई है उससे इसके अशान्त बन जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसी कारण हिन्दमहासागरीय देशों ने इसे 'शान्त-जलक्षेत्र' बनाए रखने की पुर्जोर माँग की है और संयुक्तराष्ट्र महासभा ने इस आग्रह का एक प्रस्ताव भी

पारित किया है। जब से अमेरिका ने डिवागो गसिया में नौसैनिक प्रभु बनाने का फैसला किया, तब से बड़ी शक्तियों की एशियायी राजनीति में और भी सरगर्मी पैदा हो गई है। हिन्दमहासागर में अमेरिका और सोवियत संघ की नौसैनिक शक्ति के बारे में परस्पर विरोधी अनुमानों के कारण सही स्थिति का पता लगाना सम्भव नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यमन और सोमालिया के बन्दरगाहों में नौसैनिक सुविधाएँ प्राप्त करने के बाद सोवियत नौसेना हिन्दमहासागर में अमेरिकी नौसेना के लिए चुनौती बन गई है। हिन्दमहासागर में चीन की नौसेना का भी दखल है, किन्तु शक्ति-सन्तुलन की दृष्टि से वह अधिक महत्व नहीं रखता है। यह अवश्य है कि बड़ी शक्तियों की एशियायी नीति के सन्दर्भ में चीन अपना महत्व समझता है और तदनुसार भूमिका निभा रहा है।

1950 के कोरिया-युद्ध के बाद से ही चीन एशिया की राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगा। 1954-58 का समय उसकी इस सक्रियता का वाण्डुंग चरण रहा जबकि चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने कई एशियायी देशों की यात्रा की और वहाँ की सरकारों को यह विश्वास दिलाया कि चीन उनके साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करते हुए रहना चाहता है। इससे पूर्व 1950 में तिब्बत का स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त कर चीन उसका अपने भू-भाग में विलयन कर चुका था जिसके कारण दक्षिणपूर्वी एशिया के देश चौकन्ने हो गए थे। इसी समय चीन और भारत में घनिष्ठता बड़ी और 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के नारे से दोनों देशों का आकाश गुँजा परन्तु 1958 में अकनाई चीन में चीन की घुसपैठ के साथ ही यह स्वप्न भग्न हो गया। दक्षिणपूर्वी एशिया के सभी देश पुनः सतर्क हो गए लेकिन भारत ने फिर भी सम्बन्ध सुधारने का एकतरफा प्रयास जारी रखा। चीन ने इसे भारत की कमजोरी समझा और 1962 में सुला आक्रमण कर उसका हजारों वर्गमील का क्षेत्र हथिया लिया। यह वह समय था जब विगतनाम युद्ध उत्तरोत्तर तेज होता जा रहा था और चीन का प्रभाव रोबता अमेरिका की दक्षिण-पूर्वी एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण भग्न था। इसलिए 1958 में जब चीन ने अपने क्वे-माय और मात्सू द्वीपों पर अधिकार करना चाहा तो अमेरिका ने उसे बड़ी चेतावनी दी।

विगतनाम से अमेरिका सैनिकों की वापसी के वावजूद दक्षिणपूर्वी एशिया में अमेरिका अपनी राजनीतिक गोठियाँ बेटा रहा है। विगतनाम युद्ध के दौरान चीन और अमेरिका दोनों को ही यह अहसास हो गया कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं कर सकना, उसका राजनीतिक हल खोजना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें यह भी महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में युद्ध-स्थिति सोवियत प्रभाव को ही बढ़ाने में सहायक होगी। चीन और अमेरिका दोनों ही के लिए यह स्थिति निरापद नहीं थी। अगली प्रतिद्वन्द्विता पहले भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थी और आज भी उन्ही में है, धनः अमेरिका, सोवियत संघ के प्रभार-विस्तार को अनदेखा न तब कर सकना था और न अब। ऊपर सोवियत संघ और चीन के बीच पुराना सीमा-विवाद बना

आ रहा था जो अब और भी गहरा हो गया है अतः चीन भी सोवियत संघ के प्रभाव-विस्तार के विरुद्ध था। भारत, जापान, इण्डोनेशिया एवं फिलीपीन के साथ भी चीन के सीमा-विवाद हैं। इस सब की स्वाभाविक परिणति चीन और अमेरिका के सम्बन्धों में सुधार के रूप में हुई। 1965 में जब सोवियत संघ और चीन का विवाद काफी बढ़ गया, तो अमेरिका और चीन के बीच सम्बन्ध सुधारने का सिलसिला भी आरम्भ हो गया जो 1971 में कीसिंगर की और 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन-यात्रा का हेतु बना।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 1965 में ही अमेरिका पूरी तरह से वियतनाम-युद्ध में डूब चुका था। फरवरी, 1965 में अमेरिका ने उत्तर-वियतनाम पर भीषण बमबर्षा की, किन्तु चीन ने मौलिक समर्थन के अलावा उत्तर-वियतनाम को और कोई सहायता नहीं दी। यही नहीं, बाद के वर्षों में उसने अपने इलाके से उत्तर-वियतनाम को सोवियत सैनिक सहायता भेजे जाने पर भी प्रतिवन्ध लगा दिया। इस लिए यह कोई मयोग नहीं था कि 1971 में जब एक ओर चीन और अमेरिका के बीच हिङ्-पाङ् कुटनीति चल रही थी, दूसरी ओर अमेरिकी बमबर्षक उत्तर-वियतनाम की ईंट से ईंट बजाने पर पुने हुए थे। वास्तविकता तो यह है कि जब फरवरी, 1971 में अमेरिका और दक्षिण-वियतनाम ने मिलकर लाओस पर हमला किया, तभी चीन को यह आश्वासन दे दिया गया था कि आक्रमण से उसकी सीमाओं को कोई खतरा नहीं पहुँचेगा। चीन ने इस पर विश्वास किया तभी तत्कालीन अमेरिकी विदेश-मन्त्री रोजर्स यह कह सके कि कोरिया-युद्ध के दिन लड़ चुके हैं और लाओस में चीन की ओर से प्रत्याक्रमण की कोई आशंका नहीं है।

1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद चीन और पाकिस्तान के सम्बन्धों में तेजी से सुधार भी इसका प्रमाण है कि चीन और अमेरिका के बीच सम्बन्ध-सुधार का सिलसिला 1965 के आसपास ही शुरू हो गया था। 1962 में चीन के आक्रमण के समय भारत को सहाय्य देने के लिए तत्पर अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के सम्बन्ध-सुधार का कभी विरोध नहीं किया। सेटो का सदस्य पाकिस्तान चीन से घनिष्ठता बढ़ाए और अमेरिका चुप रहे, यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं थी।

सोवियत संघ ने इस सारी स्थिति की गम्भीरता को अनदेखा नहीं किया। उससे भारत-चीन सीमा-विवाद से लाभ उठाया और भारत की ओर मंत्री का हाथ बढ़ाया। भारत को भी सोवियत संघ की मित्रता की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध के कारण भारत और अमेरिका के सम्बन्ध उत्तरोत्तर तनावपूर्ण बनते जा रहे थे। 1961 की जुलाई में कीसिंगर की चीन-यात्रा के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका और चीन की ब्यूट-रचना दक्षिण पूर्वी एशिया में सोवियत-प्रभाव को रोकने के लिए है तो सोवियत संघ ने भारत के साथ वह सन्धि-सम्पन्न करारी जिस पर दोनों देश एक धरत से विचार-विमर्श कर रहे थे। सोवियत-भारत सहयोग की यह सन्धि इसलिए और भी सम्भव हो सकी कि उस समय वगलादेश के

मुक्ति-सघर्ष के कारण भारत और पाकिस्तान एक और युद्ध के कगार पर खड़े थे तथा चीन और अमेरिका युद्ध होने पर पाकिस्तान का पक्ष लेगे, यह उनके रवैये से स्पष्ट था। भारत को सोवियत-समर्थन की ही आशा थी जो उसे सन्धि से पूर्व भी मिल रहा है।

दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद सार्वभौम बंगलादेश की स्थापना अमेरिका और चीन दोनों को ही समान रूप से अखरी, क्योंकि यह स्पष्टतः उनकी एशियायी नीति की पराजय थी, किन्तु परिस्थितिवश उन्हें यह कड़वा घूँट पीना पड़ा। चीन हिमालय में सम्भावित छेड़छाड़ इसलिए नहीं कर सकता कि तब चीन की पश्चिमोत्तर सीमा पर सोवियत संघ द्वारा कार्यवाही किए जाने की आशंका थी, और अमेरिका उन दिनों पूर्वी एशिया में बुरी तरह फँसा हुआ था यद्यपि उसने प्रशान्त महासागर स्थित सातवें बेड़े के परमाणु युद्धपोत 'एंटर्प्राइज' को बंगाल की खाड़ी में भेजकर युद्ध पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने की कोशिश की थी।

और यही से बड़ी शक्तियों की एशियायी नीति में एक नया मोड़ आरम्भ होता है। राजनीतिक वाच्यताओं से विवश अमेरिका ने शीघ्र ही बंगलादेश को मान्यता दे दी और इस प्रकार बंगलादेश के मुक्ति-सघर्ष के दौरान निभाई गई भूमिका से मिले अपयश को घोना चाहा। इससे उसे लाभ भी हुआ। सोवियत संघ और भारत से मंत्री के वायजूद बंगलादेश और अमेरिका के बीच अच्छे सम्बन्ध हैं लेकिन चीन ने न केवल बंगलादेश को मान्यता नहीं दी, बल्कि अपने निपेधाधिकार का प्रयोग कर समुत्क्राष्ट्र में उसका प्रवेश भी रोक दिया। आगे चलकर विश्व-जनमत के दबाव को ध्यान में रखते हुए पहले पाकिस्तान और फिर चीन ने बंगलादेश को मान्यता प्रदान कर दी।

बड़ी शक्तियों की एशियायी नीति की दृष्टि से 1965 के बाद का काल उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण बनता गया। इससे पूर्व विभाजनग्रस्त कुछ देशों को छोड़ कर प्रायः अन्य सभी देश पश्चिमी गुट यानी अमेरिका के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव में थे। पश्चिमी एशिया में 'सैटो' और दक्षिण पूर्वी एशिया में 'सीएटो' सैनिक सन्धियों के माध्यम से अमेरिका इस भू-भाग के मामलों में प्रायः हस्तक्षेप करता रहा परन्तु 1965 के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ। पश्चिमी एशिया में ईराक, सीरिया आदि से सोवियत संघ के सम्बन्धों में सुधार हुआ तो दक्षिण में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के खुले समर्थन के कारण भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध और सुदृढ़ हुए। उधर स्वेज से अपनी सेना वापस बुलाने के त्रिनानी निर्णय ने दक्षिण-पूर्वी एशिया और हिन्दमहासागर में भूम्य की स्थिति पंदा कर दी। हिन्दचीन देशों को छोड़कर पूर्वी एशिया के अन्य देशों को त्रिनानी निर्णय से स्वतन्त्र नीति अपनाने का अवसर मिला और इण्डोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन और थाईलैंड ने मिलकर अगस्त, 1967 में एक नया संगठन 'दक्षिण पूर्वी एशियायी संघ' बनाया।

जून 1967 में पश्चिमी एशिया में अरब-इजरायल युद्ध हुआ और अमेरिका द्वारा इजरायल का पक्ष लिए जाने के कारण अरब देशों के साथ उसके सम्बन्धों में

दरार पैदा हो गई। इससे पश्चिमी एशिया में सोवियत संघ को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस प्रकार सारे एशिया में सोवियत-प्रभाव का विस्तार हो गया।

दक्षिण पूर्वी एशिया में एक नया संगठन जन्म ले ही चुका था। पश्चिमी एशिया में भी अरब देश इजरायल से लोहा लेने के लिए एक महासंध बनाने पर गम्भीरता से विचार कर रहे थे। मित्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति नासिर की इस दिशा में कुछ सफलता मिली। वह स्थिति सोवियत नीति के अधिक अनुकूल थी, क्योंकि सोवियत नेता 1955 से ही इस बात पर जोर दे रहे थे कि सभी देशों के 'संगुक्त प्रयासों से ही शान्ति और बारतविक सुरक्षा' मिल सकती है। अतः 1969 में कम्युनिस्ट पार्टियों ने मास्को-सम्मेलन के दौरान सोवियत नेता ब्रेझ्नेव ने एशियायी सामूहिक सुरक्षा का विचार प्रस्तुत किया। पश्चिमी-गुट ने इसे चीन को अकेला करने के पड्यन्त्र के रूप में देखा। चीन भी तब तक सम्भवतः अमेरिका के बहुत नजदीक पहुँच चुका था, अतः उसने भी एशियायी सामूहिक सुरक्षा के विचार का यह कह कर खुल कर विरोध किया कि ऐसा करके सोवियत सब ने बार-बार इस बान पर जोर दिया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि वह तो यह मानता है कि एशियायी सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब चीन भी उसमें शामिल हो। लेकिन चीन ने अब तक इस दिशा में कोई एचि नहीं दिखाई है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी मास्को-यात्रा के समय एशियायी सामूहिक सुरक्षा के विचार का स्वागत किया। शायद उन्हें यह अहसास हो गया था कि एशिया में बड़ी शक्तियों की चौधराइट का युग अब समाप्त हो गया है। पिछले एक दशक में एशिया की राजनीति में आए परिवर्तनों को देखते हुए निक्सन का ऐसा कुछ सोचना स्वाभाविक ही था। लेकिन यूरोप में दो महायुद्ध लड़ने के बाद बड़ी शक्तियों ने, लगता है शायद यह फैसला कर लिया है कि यदि तीसरा महायुद्ध हुमा तो वह एशिया में लड़ा जाएगा। अतएव अब उन्होंने हिन्दमहासागर को अपनी कूटनीति का मोहरा बनाया है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया—बदलते आर्थिक समीकरण

आर्थिक समीकरण राजनीतिक समीकरणों के लिए पृष्ठभूमि का काम करते हैं और यह भी होता है कि राजनीतिक समीकरण आर्थिक समीकरणों को दिशा देते हैं। एशियायी जागरण राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक सभी क्षेत्रों में प्रसारित हो रहा है। 9 फरवरी 1975 के दिनमान में विद्वान् लेखक श्री गिरजेश पन्त ने दक्षिण पूर्वी एशिया के बदले आर्थिक समीकरणों की जो समीक्षा की थी वह एशियायी जागृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष को आलोकित करती है। अग्रिम विवरण उन्हीं के शब्दों में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समीकरण जहाँ महाशक्तियों के पारस्परिक आर्थिक राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर परिभाषित होते हैं, वहीं तीसरी दुनिया के नाम

तथाव्यति विकसशील राष्ट्रों के आधिक-राजनीतिक तन्त्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरे विश्वयुद्ध के साथ जब यूरोप के राष्ट्रों ने अमेरिकी प्रभुता को स्वीकार किया और अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवाद की सुरक्षा एवं साम्यवाद के बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए रूस-विरोधी मोर्चा कायम किया तो सम्पूर्ण विश्व शीतयुद्ध के प्रभाव से ग्रस्त हो गया। दो शिविरों में बँटी दुनिया ने उपनिवेश के जाल के बाहर निकले तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के सामने एक प्रश्न रख दिया कि वे कहाँ जाएँगे। जिन प्रकार के राष्ट्रीय आन्दोलनों से इन राष्ट्रों में राष्ट्रीय सरकार बनी तथा जिस वर्ग ने सत्ता की बगडोर सम्भाली उसके हित में यह नहीं था कि वह साम्यवादी पक्ष की ओर अपना भुकाव जाहिर करे, विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि सोवियत संघ यथास्थितिवादी (स्टेट्सको) राजनीति के विरुद्ध था। साथ ही यह भी बहुत उचित था कि नवोदित राष्ट्र अमेरिकी शिविर में चले जाएँ। पश्चिम की ओर इन राष्ट्रों की नीति मुख्यतः इन राष्ट्रों के सत्ताधारी वर्ग की सुरक्षा से प्रभावित हुई। जिन राष्ट्रों में सत्ताधारी वर्ग घरेलू राजनीतिक वर्ग और आर्थिक स्थिति पर नियन्त्रण करने में समर्थ नहीं थे, उन्होंने सीधे पश्चिम की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया। अमेरिका क्योंकि इन क्षेत्रों को अपने प्रभावक्षेत्र में रखने की उत्सुक था, अतएव उसने इनका स्वागत किया। दक्षिण-पूर्वी एशिया में 'सीएटो' की स्थापना एक ऐसा ही प्रयास था। इसके विपरीत कुछ राष्ट्रों ने दृढ़ नीति की घोषणा की—भारत, इण्डोनेशिया, इत्यादि राष्ट्र इस श्रेणी में आते हैं। यद्यपि इन राष्ट्रों ने पश्चिम के साम्राज्यवाद के विरोध में आवाज बुलन्द की लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वे राष्ट्र एक सीमा के बाद पश्चिम का विरोध करने में सक्षम रहे। एशिया एवं अफ्रीका राष्ट्रों के सम्मेलन हम बात की पुष्टि करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दो महाशक्तियों की विश्व-संरचना में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने अपने को खपाने की कोशिश की, लेकिन निर्देश महाशक्तियों के थे। दो खण्डों में टूटी दुनिया ज्यादा दिन न चल सकी, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को ही यह अहसास हो गया कि समय आ गया है जबकि 'शान्ति और सह-अस्तित्व' के आधार पर एक मैत्रीपूर्ण विश्व की संरचना की आवश्यकता है। निरसन-श्रेष्ठनेव वार्ता ने नए विश्व की आधारशिला रखी। साथ ही विश्व-मंच पर नई शक्तियों के रूप में जापान, यूरोप एवं चीन का उदय हुआ। अब विश्व दो अभिनेताओं का मंच न रहकर पाँच शक्तियों के पारस्परिक निर्णयों से प्रभावित होने लगा है और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को हम नए शक्ति-सन्तुलन में अपना स्थान चुनना पड़ेगा।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के पिछड़े हुए राष्ट्र भी विश्व-रामच पर हुए परिवर्तनों के अनुसार अपनी स्थिति बनाते-बिगाड़ते रहे। अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था, उप-व्यवस्था में जोड़-फोड़ मिटाने हुए राजनीतिक परिस्थितियों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के नेतृत्व के बारे में भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पना की। अमेरिकी, ब्रितानी एवं फ्रांसेजिया के पण्डितों की एक परिष्करण यह थी कि दक्षिण-पूर्वी एशिया का नरुणा जापान, भारत और फ्रांसेजिया के प्रभाव में योगा। तीन प्रजातन्त्र हम क्षेत्र को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करेंगे; लेकिन स्वयं भारत के प्रजातन्त्र के प्रति जापान पण्डितों को

यह लगा कि इस शृंखला से भारत को हटाकर सुहातों के इण्डोनेशिया को जोड़ने से पूरा-पूरा पश्चिमी नक्शा खिंच जाएगा। दोनों ही परिकल्पनाएँ साम्यवाद के लतरे से बचाने के लिए थी। साम्यवादी शिविर के विखण्डित होने से जापानी आर्थिक विकास की चोट ने और चीन के अशुभदय ने राजनीतिक पण्डितों के अनुमानों में परिवर्तन किए। चतुर्मुखी चीन, जापान, सोवियत संघ एवं अमेरिका के रूप में एक नए शक्ति-सन्तुलन की परिकल्पना की जाने लगी। इस नए शक्ति-सन्तुलन को विश्व के राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों से अलग नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि जापान और चीन को रूस और अमेरिका के समकक्ष स्तर पर नहीं रखा जा सकता, लेकिन यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के सम्बन्ध में दोनों ही महाशक्तियों की पारस्परिक टकराहट या समझौते से जो विषय-रंगमंच बनता या बिगड़ता है उसमें तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की क्या भूमिका रहनी है या फिर उनको क्या मिलता है। क्या विकासशील देशों के नाम से अलग होने वाले ये राष्ट्र महाशक्तियों के नियंत्रणों के अनुसार अपनी स्थिति को उनके अनुकूल बनाते रहेंगे दक्षिण-पूर्वी एशिया के बदलते हुए आर्थिक समीकरणों में जापान की नई भूमिका यह संकेत करती है कि इन पिछड़े राष्ट्रों के आसक्त तो बदलते रहने हैं, लेकिन इनकी अपनी स्थिति लगभग वही बनी रहनी है। उनके कोयले, जस्ता, रबड़, तेल और चाय के बागनों का लाभ कभी एक अथवा दूसरी महाशक्तियों को मिलता रहता है। स्वयं ये राष्ट्र एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश में दो कदम पीछे हटते रहे हैं।

इस शताब्दी में सन् 1960 के दशक के अन्तिम चरण से ही दक्षिण-पूर्वी एशिया में बाहरी शक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन प्रारम्भ हो गए थे। यह बदलाव विश्व-शक्तियों के शक्ति-सन्तुलन के नए मूल्यांकन के कारण हुआ। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन शक्तियों के बीच स्पर्धा समाप्त हो गई। सन् 1969 में 'निवमन सिद्धान्त' की शुरुआत सन् 1972 में राष्ट्रपति निवमन की चीन-यात्रा, सन् 1973 के वियतनाम-समझौते के कारण तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव की वृद्धि के कारण अमेरिकी गणना में दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्थिति में परिवर्तन आया। साम्यवाद को रोकने के लिए साम्यवादी शिविर के टूटने के बाद 'मोमिना सिद्धान्त' की कोई आवश्यकता नहीं रह गई किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया से पूरी तरह हट रहा है। निवमन के 'गोरेवपूर्ण शान्ति' के सिद्धान्त ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया में यद्यपि वियतनाम जैसे स्तर पर शामिल नहीं होना चाहेगा, लेकिन किसी भी शक्ति-सपठन में वह अपनी भूमिका चालू रखेगा। इस बीच जून, 1969 से ही रूस ने विश्व के इस हिस्से में अपनी रुचि को 'सामूहिक सुरक्षा' के नाम से प्रकट किया। यद्यपि ब्रिम्नेव ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि यह सुरक्षा-सपठन किस प्रकार के भय के लिए है, तथापि सोवियत संघ की यह नई राजनीति 'यथास्थिति' बनाए रखने के लिए

थी, जिससे कि इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोका जा सके। यह ठीक है कि चीन विश्व-स्तर पर रूस से एक कदम शायद पीछे हो लेकिन अधिकांश क्षेत्रीय साम्यवादी पार्टियों का चीन के प्रति रहल यह जाहिर करता है कि उस क्षेत्र में रूस के साम्यवादी नेतृत्व की चीन से सीधी टकराहट है। चीन भी निश्चय ही यह चाहेगा कि इस क्षेत्र को बाहरी शक्तियों के प्रभाव से बचाया जाए। इस दृष्टि से चीन और जापान की घटती दूरियाँ विश्व-महाशक्तियों को आसानी से स्वीकार नहीं होगी। जापान और चीन के बीच आर्थिक सम्बन्धों का विकास इस बात की ओर संकेत करता है कि अपनी आर्थिक, सैन्य सीमाओं एवं आवश्यकताओं से विगत ये राष्ट्र सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र में विश्व-महाशक्तियों के प्रभाव को कम करना चाहेंगे। जापान के आर्थिक चमत्कार ने जापान को दक्षिण-पूर्वी एशिया में ही नहीं वरन् विश्व-स्तर पर भी आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। अपनी आर्थिक प्रगति के कारण जापान किसी भी रूप से उपेक्षित नहीं किया जा सकता। यह निश्चय ही दिलचस्प सत्य है कि रूस ने जापान को अपनी 'सामूहिक सुरक्षा' संरचना का भागीदार बनाया। यह बात दूसरी है कि जापान ने यह कह कर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि चीन की अनुपस्थिति में वह इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था में सम्मिलित नहीं होगा। नए सन्दर्भों का एक अन्य दिलचस्प पक्ष यह है कि जापान, जो कि इस क्षेत्र में 'अमेरिकी एजेंट' के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, आज अनेक आर्थिक सामर्थ्य के कारण स्वयं अमेरिका का प्रतिस्पर्धी बन गया है। 'निक्सन शॉक' के बावजूद जापान की आर्थिक प्रगति ने जापान को अमेरिकी दृष्टि में 'आर्थिक काँटा' बना दिया है। न केवल अमेरिकी बाजार में वरन् यूरोप में और दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी अमेरिकी और जापानी आर्थिक स्वार्थों में सीधी टक्कर है। विशेषकर तेल-सकट के भीषण परिणामों से जस्त जापान, जो अब तक अमेरिकी निर्देशों पर अपनी विदेश-नीति को निर्धारित करता रहा था, अब यह महसूस कर रहा है कि उसको अब अपनी स्वतन्त्र नीति निर्धारित करनी होगी। इस दृष्टि में विकासशील राष्ट्रों के सन्दर्भ में, जहाँ कच्चे प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जापानी आर्थिक वृद्धिनीति में भारी परिवर्तन आया है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा

महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा एक अरसे से पश्चिमेशिया में तनाव बनाए हुए है और इस तनाव के घातक परिणामों की कल्पना इस क्षेत्र के सभी देशों की चिन्ता का कारण बनी हुई है—अफगानिस्तान में सोवियत सशस्त्र सैनिक कार्यवाही के बाद यह चिन्ता बढ़ी है और उससे विश्व-शान्ति के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। ऐसा ही खतरा दक्षिण-पूर्वेशिया की तनावग्रस्त स्थिति के कारण भी बना हुआ है। वहाँ दोनों महाशक्तियाँ ही नहीं, तीसरी महाशक्ति बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा चीन भी प्रतिस्पर्धा में है। वह नहीं चाहता है कि दक्षिण चीन सागर के जल में या हिन्द-चीन की भूमि और आकाश में किसी महाशक्ति का दखल हो, क्योंकि वहाँ

महाशक्तियों की उपस्थिति उसके विस्तारवादी इरादों पर पानी फेर देगी। अप्रैल, 1980 के दिनमान में दक्षिण-पूर्वी एशिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का जो चित्र खींचा गया है, वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए पठनीय है—

कम्बोडिया या कम्पुच्या में वियतनाम की सैनिक कार्यवाही और उसके प्रत्युत्तर में वियतनाम को 'सबक' सिखाने के लिए चीन द्वारा किए गए हमले के बाद महाशक्तियों की यह स्पर्धा खुलकर सामने आ गई। वियतनाम से हटने के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में अधिक प्रभावी नहीं रह गया था। दूसरी ओर सोवियत संघ की सक्रियता बढ़ गई। वियतनाम जैसा जुझारू साथी पाकर उसने दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। कम्बोडिया में वियतनाम का सैनिक हस्तक्षेप इस कोशिश का ही एक हिस्सा था। चीन तो सोवियत इरादे को पहले ही ताड़ गया था और उसने तत्काल वियतनाम पर आक्रमण करके सोवियत संघ को यह बता दिया कि वह इस क्षेत्र में उसे अपने पांव फँसाने नहीं देगा।

माघोत्तर चीन का अमेरिका प्रेम भी शायद इसीलिए बहुत प्रगाढ़ हो गया है। दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन को सामन्तिक खतरा फिलहाल सोवियत संघ की ओर से ही है। उसकी उत्तरी सीमा पर सोवियत संघ ने कोई 20 डिवीजन सेना तैनात रखी है। इसके अलावा उसके सैकड़ों सड़क और बगवर्क विमान तथा प्रशान्त महासागर स्थिति नौवैयक्तिक बेड़ा भी तैनात है। दोनों देशों के बीच सीमा पर मुठभेड़ें भी हो चुकी हैं। ऐसी हालत में यदि चीन की दक्षिण सीमा पर भी सोवियत प्रभाव बढ़ता है तो चीन अपने भीतर ही सिमट कर रह जाएगा। पश्चिम एशिया में चीन को पहले कोई दिलचस्पी नहीं रही—इसलिए भी वह क्षेत्र उसकी जमीन से दूर है और इसलिए भी कि वहाँ सोवियत संघ को बांध रखने के लिए अमेरिका और उसके मित्र पश्चिमी देश प्राणपरशु से लगे हुए हैं। अफ्रीका में दखल देने की कोशिश चीन ने अलवृत्ता की थी। तानजाम रेलमार्ग इसका प्रमाण है किन्तु वहाँ वह अपने प्रभाव को बनाए रखने में सफल नहीं हो सका और इसमें शायद भूगोल ही उसके आड़े आया। अफगानिस्तान में सोवियत सेना की उपस्थिति से वह अलवृत्ता चिन्तित हुआ है कि क्योंकि उससे न केवल उसकी अपनी सीमा अराधित हो गई है बल्कि उसके एक अपेक्षया नए मित्र पाकिस्तान के लिए भी सकट पैदा हुआ है।

सम्भवतः यही कारण है कि इधर दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान और आस्ट्रेलिया के माध्यम से अमेरिका ने जो अधिक दिलचस्पी दिखाई है उसे चीन कम से कम इस समय तो अनदेखा कर ही रहा है। अमेरिका का दखल दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थायी रूप से बना रहे, यह चीन निश्चय ही नहीं चाहेगा, किन्तु इस क्षेत्र से सोवियत संघ को खदेड़ने के लिए वह तत्पर दिखाई देता है। ताइवान पर उसकी चुप्पी इसका संकेत है। दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका और चीनी हितों में वस्तुतः कोई बड़ा

टकराव भी नहीं है। अमेरिका चाहता है कि सोवियत संघ पूर्वोशिया में चीन से उलझा रहे ताकि पश्चिमी यूरोप पर उसका दबाव न बढ़ सके और न ही पश्चिमोशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका आदि क्षेत्रों में वह अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने प्रयास सधन कर सके। इसके लिए जापान, आस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्वोशिया राष्ट्रमंडल (एशियान) के देशों—मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इण्डोनेशिया और फिलीपीन को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के अलावा चीन की पीठ थपथपाना भी वह जरूरी मानता है।

दक्षिण-पूर्वोशिया राष्ट्रसंघ के सदस्य देश इस क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप के खतरो को समझते हैं और चाहते हैं कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान आपस में बातचीत करके ही किया जाए। गत वर्ष दिसम्बर में उनके विदेश मंत्री कम्बोडिया या कम्पुच्या की समस्या पर विचार करने के लिए क्वालालम्पुर में एक दिन के लिए मिले थे। इस मुद्दे पर उनमें तब आम सहमति पाई गई। उसी बैठक में उन्होंने अपनी स्थायी समिति के अध्यक्ष मलेशिया के विदेशमन्त्री अहमद रिताउद्दीन को वियतनाम भेजने का फैसला किया था ताकि दोनों पक्षों के बीच सम्वाद शुरू हो सके किन्तु बाद की घटनाओं से स्थिति में परिवर्तन हुआ—और खासतौर से अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सैनिक कार्यवाही ने एशियान के सदस्य देशों के कान खड़े कर दिए और वियतनाम तथा कम्बोडिया के प्रति उनका रवैया संस्त हो गया। इसके विपरीत अब वे एक ऐसे शक्ति-मन्तुलन के पक्ष में दिखायी पड़ते हैं जिसमें सोवियत संघ और वियतनाम की तुलना में पश्चिमी गुट और चीन का पनडा भारी हो।

इस सन्दर्भ में दक्षिण-पूर्वोशिया सन्धि संगठन (सीएटो) को पुनर्जीवित करने की चर्चा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशान्त महासागर में गिम्पेक-80 के नाम से जाने गए नौसैनिक अभ्यास को सीएटो को पुन सजिव बनाने की दिशा में एक बंदम माना जा रहा है। आस्ट्रेलिया इस अभ्यास में एक प्रमुख भागीदार है और वह इन क्षेत्र के देशों को पश्चिमी गुट के समर्थन में खड़ा करने के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। इसके लिए वह प्रति वर्ष तीन करोड़ डॉलर की सैनिक सहायता इन देशों को देता है और उनके लिए हर प्रकार के सैनिक उपकरणों का संभरण भी करता है। इसके अलावा एशियान के सदस्य देशों के हजारों छात्र आस्ट्रेलिया के सैनिक विद्यालयों में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इनमें 1,500 से अधिक मलेशियाई और अब हजार से ऊपर इण्डोनेशियाई छात्र होते हैं। सिंगापुर के छात्रों का एक दल भी सैनिक प्रशिक्षण के लिए भीष्ट ही आस्ट्रेलिया जाने वाला है। वास्तव में अमेरिका चाहता है कि एशियान के देश न केवल गिम्पेक-80 नौसैनिक अभ्यास में भाग ले बल्कि इस क्षेत्र में उसकी अन्य गतिविधियों में भी भागीदार बनें। इसी दृष्टि से इन देशों को भारी मात्रा में सैनिक सहायता देने के लिए भी तत्पर है। गत वर्ष थाईलैंड को दी गई सैनिक सहायता इसका प्रमाण है और इन बात का भी कि यह सीएटो को पुनर्जीवित करने के लिए उन्मुख है।

वस्तुतः वह एशियान के सदस्य देशों को एक ऐसे गुट का रूप देना चाहता है जो राजनीतिक और अन्ततः नैतिक दृष्टि से भी साम्यवाद विरोधी हो।

इस दिशा में चीन भी उसका सहायक बनने के लिए तत्पर जनि पड़ता है। दक्षिण-पूर्वशिया के लिए पीकिंग की अपनी एक सुनिश्चित विस्तारवादी नीति है जिसे क्रियान्वित करने के लिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में सोवियत और अमेरिकी गुटों में टकराव हो। चीनी नेतृत्व यह मानता है कि ऐसे सधर्ष में इन दोनों ही गुटों की शक्तियाँ क्षीण होगी और वह इस क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीति को आसानी से क्रियान्वित कर सकेगा। एशियान देश चीन के इस दूरगामी इरादे के प्रति मतर्क दिखाई पड़ते हैं। कम्बोडिया के मामले में एशियान देशों का समर्थन जुटाने के लिए चीनी विदेश मन्त्री ने हाल में फ़िरीरीन, मियापुर और मनयेशिया का दौरा किया जिसके दौरान इन देशों ने उन्हें साफ़ तौर से बता दिया कि कोई भी एशियान देश महाशक्तियों के मध्य में भागीदार बनना नहीं चाहता।

इधर दक्षिण चीन सागर के उथले जल में तेल मिलने की सम्भावना ने स्थिति को एक नया मोड़ दे दिया है। कई तटवर्ती देशों ने इस सम्भावना को देखते हुए दक्षिण चीन सागर के जल पर बढ़ा-बढ़ा कर अपने-अपने दावे पेश कर दिए हैं। इंडोनेशिया ने तो 25,000 कि. मी. क्षेत्र में तेल की खोज के काम का ठेका भी तीन अमेरिकी कम्पनियों को दे दिया है और उसने वहाँ नौमनिक अभ्यास भी किया है। इस क्षेत्र पर वियतनाम भी अपना दावा जता रहा है। चीन कुछ वर्ष पूर्व ही बोर्नियो द्वीप से, जिनका कुछ भाग मलयेशिया का है और इंडोनेशिया कुछ मील की दूरी तक के समुद्र पर अपना अधिकार बता चुका है। इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर में मुद्द की सम्भावना देखते हुए तैयारी कर रहा है।

पारासेल और स्पाटले द्वीपसमूहों पर परस्पर विरोधी दावों में भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की सम्भावना है। चीन ने 1974 में सैनिक कार्यवाही करके पारासेल द्वीपसमूह पर अधिकार कर लिया था। उस समय तक उस पर दक्षिण वियतनाम का कब्जा था और उसकी सेना भी वहाँ थी जिसे चीनी सेना ने खदेड़ दिया। दक्षिण वियतनाम का अब अबग कोई अस्तित्व नहीं रहा और माना जा सकता है कि वियतनाम की मौजूदा सरकार भी पारासेल को अपना क्षेत्र मानती है। हालाँकि उसने अभी उसे चीन से मुक्त कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की किन्तु 1975 में स्पाटले द्वीपसमूह में सेना भेज कर उसने चीन को यह बता ही दिया कि वह भी इन द्वीपसमूहों का दावेदार है। स्पाटले द्वीपसमूह को चीन भी अपना 'ऐतिहासिक प्रदेश' बना रहा है, क्योंकि 57 द्वीपों के इस द्वीपसमूह के एक द्वीप पर ताइवान (राष्ट्रवादी चीन) की सेना है। उधर फ़िरीरीन भी इस द्वीपसमूह के कुछ द्वीपों पर अपना अधिकार जता रहा है क्योंकि उसके अनुसार ये द्वीप स्पाटले द्वीपसमूह का हिस्सा न होकर उसके समुद्रनट से सटे रीड बैंक के ग्रंग हैं।

इस स्थिति में यह सम्भावना तो है ही कि दक्षिण-पूर्वशिया में व्याप्त तनाव

कभी भी उग्र संघर्ष का रूप ले सकता है। चीन और वियतनाम दोनों ने ही फिलीपीन को अलग-अलग यह आश्वासन दे रखा है कि सीमा-विवाद को शान्तिपूर्ण ढंग से परस्पर बातचीत के द्वारा ही हल किया जाएगा, अमेरिका और फिलीपीन के बीच परस्पर सुरक्षा सन्धि है। यदि फिलीपीन पर हमला हुआ तो वह अमेरिका से सैनिक सहायता पाने की आशा कर सकता है। इस सन्धि के रहते चीन या वियतनाम आसानी से फिलीपीन को नहीं छेड़ेंगे किन्तु चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष की सम्भावना तो है ही, चीनी नेतृत्व विमननाम को दूसरा सबक सिखाने के लिए तत्पर जान पड़ता है। चीन किसी भी समय वियतनाम अधिकृत स्पार्टले द्वीपों पर अधिकार जमाने के लिए कार्यवाही कर सकता है। ऐसी हालत में सोवियत संघ प्रज्ञान्त स्थित अपने सशक्त नौसैनिक बेड़े को वियतनाम की सहायता के लिए हरकत में नहीं लाएगा, इसकी कोई गारण्टी नहीं है। सोवियत संघ की कोशिश है कि वियतनाम पूर्वशिया में उसके लिए वही भूमिका निभाए जो कि अटलांटिक महासागर में क्यूबा निभा रहा है। अतः भावी चीन-वियतनाम संघर्ष में सोवियत संघ के सक्रिय भाग लेने की सम्भावना तो है ही। यदि ऐसा हुआ तो दक्षिण-पूर्वशिया में व्यापक संघर्ष छिड़ सकता है।

सच तो यह है कि इस क्षेत्र के सभी देश और उनके मित्र बड़ी शक्तियाँ यह मानकर चल रही हैं कि यहाँ कभी भी युद्ध छिड़ सकता है और इसे ध्यान में रखकर ही वे सभी अपनी-अपनी व्यूहरचना कर रहे हैं।

दक्षिण-पूर्वशिया में अमेरिका का बहुत कुछ दाँव पर लगा है। जहाँ चीन अपने पाँव के नीचे की सोच कर अपनी शोटियाँ बिटा रहा है, अमेरिका की दक्षिण-पूर्वशियायी नीति उसकी पश्चिमेशिया और यूरोप की नीतियों से जुड़ी है। अमेरिका के वियतनाम से हटने के बाद से पश्चिमेशिया और यूरोप में सोवियत संघ का दबाव अधिक बढ़ गया है, जो अमेरिकी हितों के विरुद्ध है। यह दबाव कम करने के लिए अमेरिका यह जरूरी मानता है कि सोवियत संघ दक्षिण-पूर्वशिया में उलझे। इस क्षेत्र में युद्ध भड़काने पर सोवियत संघ के विकल्प सीमित हो जाएँगे और अफगानिस्तान में सैनिक कार्यवाही करके उमने जो प्रभाव अर्जित किया है वह भी बहुत कुछ निरस्त हो जाएगा। ऐसी हालत में महाशक्तियाँ निकट भविष्य में ही दक्षिण-पूर्वशिया में जोर आजमाइश करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

महाशक्तियाँ और एशिया में युद्ध का बढ़ता संकट

पिछले दशक में एशिया और हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों में विस्फोटक स्थिति निरन्तर उभर रही है और अनेक तनाव-क्षेत्र पैदा हो गए हैं। इन क्षेत्रों में महाशक्तियों की आपसी प्रतिद्वन्द्विता और राजनीतिक सैनिक रस्सा-बस्सी चल रही है और राजनीतिक क्षेत्रों में यह आगवा व्याप्त है कि नौवें दशक में घमासान युद्ध का विस्फोट हो सकता है और महाशक्तियों के निहित स्वार्थों के कारण यह युद्ध तृतीय विश्वयुद्ध का रूप धारण कर सकता है। एशिया में युद्ध के इस बढ़ते संकट पर

जनवरी 1981 के साप्ताहिक हिन्दुस्तान में श्री सुब्रह्मण्यम का जो लेख प्रकाशित हुआ है, वह वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है—

इतिहास ने पहले कभी हिन्द महासागर में महाशक्तियों के नौनैतिक बेड़ों का जमघट नहीं देखा, जैसा कि आज है। सारे एशिया में और हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों में अनेक तनाव-क्षेत्र पैदा हो गए हैं। ईरान और ईराक, सोमालिया और इथियोपिया की सीमाओं पर युद्ध की आग धधक रही है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की घुसपैठ, एरितोरिया, कुवैस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पाई-कम्प्यूच्या सीमा, उत्तरी बर्मा, उत्तर-पूर्व पाई देश और पाई-मलेशिया सीमा—सब ओर संपर्क के बादल भँडरा रहे हैं। चीन और वियतनाम में सीमाओं को लेकर तनाव जारी है। सीरिया-जोर्डन तथा सीरिया-इजरायल सीमा की हालत भी यही है। इन स्थानीय संघर्षों की प्रतिक्रियास्वरूप महाशक्तियों का आपसी तनाव भी बढ़ रहा है। इस तरह स्थिति धीरे-धीरे और भी विकट होती जा रही है।

अब एक नया शीत-युद्ध तेजी पकड़ रहा है। दुर्भाग्यवश इस बार इसका क्षेत्र एशिया और हिन्द महासागर के तटवर्ती देश हैं। शीत-युद्ध इसे यों कहा जाता है कि महाशक्तियाँ आपसी प्रतिद्वन्द्विता और राजनीतिक-सैनिक रस्साकसी को कुछ ऐसे चलाती हैं कि दोनों में सामने-सामने सैनिक मुठभेड़ न हो। इसका सम्बन्ध किसी आदर्शवाद से नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। सन् 1946 से 1973 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत-युद्ध जारी रहा उसका भी किसी आदर्शवाद से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था। यह तो शक्ति के लिए सीधी-सीधी खींचतान थी। स्तालिन ने पश्चिमी शक्तियों को इस बात का पूरा मौका दिया कि वे यूनान की कम्युनिस्ट पार्टी का कधुमर निकालें। सत्ता की बागडोर चीनी साम्यवादियों के हाथ लगे, इसके लिए भी वह कभी इच्छुक न थे। पाल्टा और पोत्सदाम अनुवन्धों के अनुरूप उसने पूर्वी यूरोप पर अपना शिकजा बहुत मजबूत रखा, ताकि परमाणु शक्ति से लैस पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध एक प्रबल सुरक्षा-व्यवस्था बनाई जा सके। अमेरिका की यह प्रबल आकांक्षा थी कि सोवियत संघ को सामरिक शक्ति में बराबरी तक न पहुँचने दें और उसके प्रभाव-क्षेत्रों की सीमा को वापस 1939 की स्थिति में धकेल डाले। अपने-अपने हितों के लिए ये चालें चलने को दोनों ही ताकतों ने आदर्शवाद के लवादे ओढ़ लिए।

1946 से 1973 के बीच यूरोप में शीतयुद्ध की जो खींचतान रही, एशिया में चलने वाला वर्तमान संघर्ष उससे कहीं ज्यादा जोखिमभरा है। उस समय तो पाल्टा और पोत्सदाम सम्मेलनों ने शीतयुद्ध की लक्ष्मण-रेखाएँ खींच दी थी। यूरोप की स्थिति यह है कि वहाँ के राष्ट्र, सन्धियों और अपनी-अपनी प्रभुसत्ता की सीमाओं में परम्परागत रूप से सिमटे हुए हैं। वहाँ जो कुछ भी ठण्डा संपर्क हुआ वह सुव्यवस्थित सैनिक सन्धियों वाले गुटों के बीच हुआ जिनके नेताओं के बीच संचार-सम्पर्क बढ़ा सुव्यवस्थित था। ये सारे मुद्दे शीतयुद्ध को किसी भयंकर युद्ध में परिणत होने से रोकने वाले सिद्ध हुए।

लेकिन एशिया और हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों की स्थिति एकदम भिन्न है। यहाँ तो अधिकांश देश गुट-निरपेक्ष हैं, जिन्हें उपनिवेशवादी भेड़ियों से नष्ट-नष्ट ही छुटकारा मिला है। इनमें बहुत-से देशों पर या तो एक छोटा शासक-वर्ग सत्तारूढ़ है या ये किसी एक शासक के अधीन हैं। इस प्रकार बहुसंख्यक मध्य-वर्ग का वहाँ निर्णय लेने में कोई हाथ नहीं रहता। अगर इस छोटे गुट को कोई मोटी रिश्तत मिल जाए या किसी पड़ोस के द्वारा उसका सत्ता पलट दिया जाए तो उस राष्ट्र की विदेश-नीति को पूरी तरह से बदला जा सकता है। यही कारण है कि महाशक्तियाँ इन देशों के नेतृत्व के विरुद्ध होने वाली साजिशों में गहरी दिनचस्पी लेती रही हैं।

कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में मिस्र, सोमालिया, इथियोपिया के नेताओं ने अपनी विदेश नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। ईरान में शान्ति के बाद यह स्थिति आई और ईराक में इस बात के आधार साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि वहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा।

विदेश समस्याओं में इतना भारी उलट-फेर खतरे का स्पष्ट संकेत है। महाशक्तियों के किसी-न-किसी रूप में इसमें हस्तक्षेप अथवा जल्दी में लिए गए फैसले या अनुमान की गलतियों से अगर कोई सीधा सैनिक संघर्ष भड़क उठे, तो आश्चर्य न होगा। अमेरिका और चीन के बीच दीर्घकालीन समझौता गलत पड़ने का ही परिणाम समझा जाना चाहिए। इसी तरह अमेरिका का वियतनाम युद्ध में फँसना गलतफहमियों और गलत अनुमानों का मिलाजुला नतीजा था।

एशिया और हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों में उपनिवेशवादी विरासत के फलस्वरूप बहुत से ऐसे भगड़े आज भी मौजूद हैं, जिन्हें सुनभाया नहीं जा सके। इनका कारण है, स्वाभाविक रूप से एकरस राष्ट्रों और देशों के बीच राजनीतिक सीमा-विभाजन। इसके अलावा धर्म और वर्गों के संघर्ष के कारण भी यहाँ बहुत-से चूँटे फँसे हुए हैं। परम्परागत समाजों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी अनेक प्रकार के तनावों को जन्म देती है। ऐसी हालत में अगर महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता और संघर्ष भी इनमें शामिल हो जाएँ तो परिस्थितियों के विस्फोटक होने की गुंजाइश बहुत बड़ जाती है।

इनमें से कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास तेल के अपार भण्डार हैं। इनकी पेट्रोल की बेहिसाब कमाई में से कुछ हिस्सा खमोटेने और इनके साथ निकट के सैनिक-राजनीतिक रिश्ते कायम करने के चक्कर में महाशक्तियाँ और कुछ दूरी बड़ी शक्तियाँ इन्हीं तरह-तरह के आधुनिक हथियार सप्लाई कर रही हैं। इनमें से अनेक देशों की हालत यह है कि वे तरकीबी दृष्टि में इन हथियारों को न तो हज़म कर सकते हैं, न ठीक से इनका इस्तेमाल करना जानते हैं। इस आधुनिक साज-सामान के रख-रखाव के लिए और अपने लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए इन देशों को हथियार सप्लाई करने वाले देशों के विदेशी-विशेषज्ञों पर निर्भर होना पड़ता है।

विकासशील देशों और बड़ी शक्तियों का यह रिरना उनको कितना आश्रित बना सकता है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। कभी तो यह निकटता राष्ट्र के घनत्व ही बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा कर देती है, जैसा कि ईरान में हुआ। बड़ी शक्तियों से आधुनिक हथियारों की सप्लाई अपना अलग रंग दिखाती है। एक देश हथियार पाता है, तो उसका पड़ोसी भी कहीं-न-कहीं से उसके मुकाबले के हथियार जुटाने की कोशिश करता है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए किसी देश को आधुनिक हथियार मिलने पर उसमें स्थिरता आई हो। बल्कि इसके विपरीत सम्बन्धित क्षेत्र में इससे प्रस्थिरता ही आती है।

एशिया और हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सघर्ष चल रहे हैं उनका ससार की बड़ी शक्तियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष कुञ्ज-न-कुञ्ज सिलसिला अवश्य है। हिन्द-चीन में थाई देश की सहायता अगर अमेरिका और चीन कर रहे हैं और अगर वे दोनों विघटननाम की धेरे में रखने में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं तो सोवियत संघ सीधे-सीधे विघटननाम की मदद कर रहा है। अगर सोवियत संघ करमाल की सत्ता को पूरी तरह से जमान रखने को कटिबद्ध है तो अफगानिस्तान में विद्रोही सड़कों की मदद अमेरिका कर रहा है। यदि ईरान को हथियार अमेरिका ने दिए थे तो ईराक को अधिकांश हथियार रुम से मिले। सीरिया को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त है, तो इजरायल और जोर्डन की पीठ अमेरिका थपथपा रहा है। अफ्रीका में हाल ही में सोमालिया ने अमेरिका के साथ एक सैनिक सन्धि की है, उधर रूसी दक्षिण की बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सत्ता को अमेरिका और पश्चिम के नई देशों की परोक्ष सहायता प्राप्त है, जबकि 'अखन राष्ट्र समर्थन के लिए सोवियत संघ का मुँह देवते हैं।

छठे और सातवें दशक में, जबकि यूरोप में शीतयुद्ध जोरों पर था, एशिया और हिन्द महासागर के तटवर्ती क्षेत्र के गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के लिए यह सम्भव था कि वे बड़ी ताकतों की सीखतान से दूर रहे। अब यूरोप में तो तनाव शिथिल है, लेकिन महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता वहाँ से खिसक कर एशिया और हिन्द महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में फैल गई है। अब हाल यह है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र इस प्रतिद्वन्द्विता को सीधा अपनी छाती पर भेल रहे हैं। इससे उनका विचलित हो जाना स्वाभाविक ही है। उदाहरण के लिए मिस्र, जो कि कभी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अग्रगण्य में से था, आज अमेरिका को अड्डे बनाने के लिए जगह देने को राजी हो गया है। ओमान, सोमालिया और कीनिया की हालत भी वही है। उधर खबर है कि सोवियत संघ उत्तरी यमन में अरब के अड्डे को इन्तेमात करने जा रहा है। यह भी तामाचार है कि वह दक्षिण-पश्चिम के दहलाकटों में भी एक अड्डा कायम करने का इच्छुक है। उसकी नीसेना अमेरिका द्वारा कभी विघटननाम की दानाम और कभी धीरान खाडियों में जुटाई गई सुविधाओं का आज पूरी स्वच्छन्दता से उपयोग कर रही है। जाहिर है कि महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता ने इस क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता की घजियाँ बिखेरनी शुरू कर दी हैं।

एक ओर मुद्दा भी हिन्द महासागर में सुरक्षा के लिए भारी भरकम खतरा पैदा कर रहा है। प्राप्त समाचारों के अनुसार इजरायल और दक्षिणी अफ्रीका ने गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार जुटा लिए हैं। पाकिस्तान परमाणु-क्षमता जुटाने के लिए जी-तोड़ कोशिशें कर रहा है। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन—इन पाँच बड़ी शक्तियों की परमाणु-प्रस्त्र प्रसार निरोध-सन्धि की वास्तविकता अब बदल गई है। वर्तमान राजनीतिक चालों का सकारात्मक यह है कि एक शक्ति के हाथ में वे हथियार हों और दूसरी के न हों। अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो स्वभावतः हथियारों के सैनिक प्रयोग की लालसा भी बनी रहेगी।

इन सब बातों से साफ जाहिर है कि एशिया और हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों में सैनिक भुठभेड़ का जोखिम अधिक बढ़ चुका है।

अफ्रीका में जागृति (Resurgence of Africa)

अफ्रीका महाद्वीप का परिचय

अफ्रीका लगभग 11,5,00,000 वर्गमील क्षेत्रफल वाला एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह आकार, लम्बाई और अन्य कई प्रथों में दक्षिण अमेरिका से मिलता-जुलता है। उत्तर अफ्रीका के अधिकांश निवासी गोरे हैं और शेष अफ्रीका के मूल निवासी काले हैं, लेकिन दोनों के बीच एकता और प्रेम की भावनाएँ विकसित होती रही हैं। अफ्रीका दक्षिण अमेरिका से बहुत-सी बातों में समान है। ब्रून एव ममते (Brunn and Mamatey) के अनुसार—

“दोनों अपने उत्तर में एक विशाल भू-खण्ड से एक तंग भूडमरूमध्य द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसे मानव-निर्मित नहरों द्वारा विभाजित किया गया है। दोनों लगभग एक त्रिकोण के आकार के हैं जो दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ते हुए एक पूर्ण कोण बनाते हैं। दोनों बीच में विपुल-रेखीय प्रदेशों की तरह बरसाती जंगलों और बड़ी नदियों में भरपूर है—अफ्रीका की काँगो नदी और दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी एक जैसी है। जनसंख्या का घनत्व लगभग एक-सा है जिनमें एक वर्गमील क्षेत्र में सिर्फ 20 व्यक्ति रहते हैं। दोनों साधन-मम्पन्न हैं। खनिज, पेट्रोल और जलशक्ति इतनी हैं कि उनके विकास के लिए मिर्ग पृथ्वी की आवश्यकता है। दोनों में जनसंख्या की वृद्धि की दर ऊँची और जीवन-स्तर निम्नकोटि का है। दोनों यूरोपीय उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं और दोनों ने विद्रोह करके आजादी प्राप्त की है। दक्षिण-अमेरिका के लोगों ने स्वयं को स्पेनी और पुर्तगाली शासन के शिकारों से 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही मुक्त कर लिया था। अफ्रीका की जनता 19वीं शताब्दी में अनेकों यूरोपीय शक्तियों की साम्राज्य-लिप्ता का शिकार बनी, किन्तु उन्होंने 20वीं शताब्दी के मध्य में तेज़ी से स्वतन्त्रता प्राप्त की।”

1870 के बाद से ही यूरोपीय शक्तियों में अफ्रीका में उपनिवेशों की प्राप्ति की होड़ लग गई। 1870 के बाद केवल 20 वर्ष की अल्पावधि में ही यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के लगभग 9/10 भाग को आपस में विभाजित कर लिया। 1880 में उनके पास 1 लाख वर्गमील प्रदेश था जो 10 वर्ष बाद बढ़कर 6 लाख वर्गमील हो गया। इस प्रकार 19वीं सदी के अन्तिम चरण के समाप्त होते-होते समूचा अफ्रीका महाद्वीप यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश बन गया। प्रथम महायुद्ध से पूर्व केवल एबीसीनिया ही स्वतन्त्र राज्य रह गया था, किन्तु सन् 1936 में इसकी स्वतन्त्रता भी इटली द्वारा समाप्त कर दी गई, हालाँकि द्वितीय महायुद्ध काल में यह राष्ट्र पुनः स्वतन्त्र हो गया। जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तो सम्पूर्ण अफ्रीका में केवल एबीसीनिया, साइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका का गण और मिस्र ही स्वतन्त्र या अर्धस्वतन्त्र राज्य थे। अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप विभिन्न यूरोपीय शक्तियों में इस प्रकार बँटा हुआ था—

क्र.सं.	नाम	क्षेत्रफल (वर्गमील)	1961 के अनुसार जनसंख्या
1	फ्रांसीसी अफ्रीका	40,22,150	4,41,52,600
2	ब्रिटिश अफ्रीका	20,25,719	6,24,33,645
3	बेल्जियम अफ्रीका	9,24,300	1,20,00,000
4	पुर्तगीज अफ्रीका	7,78,000	95,00,000
5	स्पेनिश अफ्रीका	1,34,200	14,95,000

द्वितीय महायुद्ध के बाद स्वतन्त्रता की लहर (1945-1974)

द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका जिसे कभी अन्ध-महाद्वीप (Dark-Continent) कहा जाता था कुछ ही वर्षों में स्वतन्त्रता के प्रकाश से आलोकित हो उठा। जिस तेजी से यूरोप के राष्ट्रों ने अफ्रीका में अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, उन्हीं की तेजी से अफ्रीका में उनके साम्राज्य का अन्त हो गया। 20 वर्ष के अल्पकाल में ही अफ्रीका के 90 प्रतिशत देश स्वतन्त्र हो गए। जाति, भाषा, इतिहास, परम्परा, धर्म आदि की विभिन्नताओं के बावजूद अफ्रीका में राष्ट्रवाद ने अग्रगण्य स्थिति ली। यह एक विनम्र घटना थी। इस राष्ट्रवाद के उदय और विस्तार के मूल में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण निहित थे—

1. यूरोप की गोरी बानियाँ अफ्रीका के अश्वेत लोगों को अपने से निम्नकोटि का मानती थीं। इस मिद्वान्त की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और अफ्रीका में राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा। राष्ट्रवाद की मुख्य प्रेरणा 'जातीय समानता' के सिद्धान्त से मिली। पारवात्य सम्पर्क और पारवात्य साहित्य के प्रसार ने भी अफ्रीका के प्रबुद्ध लोगों में राष्ट्रवाद की ज्योति जगाने में सहायता की।

2. द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की आजादी के माध्यम से एशिया के विभिन्न भागों में भी आजादी की लहर फैल गई। एशिया के राष्ट्र तेजी से स्वतन्त्र होते

गए। स्वतन्त्रता की यह लहर अफ्रीका महाद्वीप से जा टकराई और इस महाद्वीप के करोड़ों लोग स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आतुर हो उठे।

3. महायुद्ध-काल के स्वतन्त्रता-प्रेमी अमेरिकियों के सम्पर्क ने भी अफ्रीका-वासियों में स्वतन्त्रता की आकांक्षा पैदा की। राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उपनिवेशवाद के विरोध में भी अफ्रीका के राष्ट्रीय जागरण को बल मिला।

4 अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी अफ्रीका के देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता दी। महायुद्ध ने उपनिवेशवादी शक्तियों को अत्यन्त दुर्बल बना दिया। फ्रांस व ब्रिटेन आदि राष्ट्र इतने कमजोर हो गए कि उनमें अपने उपनिवेशों के स्वाधीनता आन्दोलनों का दमन करने की शक्ति नहीं रह गई। जब एशिया के उपनिवेश तेजी से उनके चंगुल से मुक्त होने लगे तो अफ्रीकी राष्ट्रवादियों में भी प्रबल आत्म-विश्वास जाग्रत हुआ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका-महाद्वीप में एक-एक करके स्वतन्त्रता की तीन उत्तरोत्तर जबर्दस्त लहरें आईं। महायुद्ध की समाप्ति पर अफ्रीका में केवल 4 राज्य स्वतन्त्र थे—एबीसीनिया, लाइबेरिया, दक्षिण-अफ्रीका संघ और मिस्र। यह 130 लाख वर्ग मील का क्षेत्र अफ्रीका-महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का केवल 11 प्रतिशत था और इसकी 28 करोड़ की आबादी अफ्रीका की कुल जनसंख्या का 26 प्रतिशत थी। इसके बाद स्वतन्त्रता की पहली लहर आई। इस लहर ने केवल अल्जीरिया को छोड़कर अरबों द्वारा आवासित शेष उत्तरी अफ्रीका से उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों का सफाया कर दिया। इस पहली लहर द्वारा स्वतन्त्र होने वाले राष्ट्रों में 1951 में स्वतन्त्र होने वाला लीबिया और 1956 में स्वाधीनता पाने वाले सूडान, मोरक्को तथा ट्यूनीशिया थे। स्वतन्त्रता की दूसरी लहर ने काले अर्थान् नीग्रो लोगों द्वारा आवासित अफ्रीका को प्रभावित किया। 1957 में ब्रिटेन द्वारा घाना को स्वतन्त्रता प्रदान की गई और 1958 में गिनी पचम फ्रांसीसी गणराज्य से पृथक् हो गया। 1959 तक अफ्रीका में ग्यारह राज्य स्वाधीन हो गए, किन्तु अभी तक सहारा के दक्षिण का और जिम्बेब्वे नदी के उत्तर का मध्य-अफ्रीका पराधीन था। 1960 में स्वतन्त्रता की तीसरी जबर्दस्त लहर आई जिमने इस क्षेत्र के अधिकांश गुलाम देशों को आजाद कर दिया। यह वर्ष अफ्रीका की स्वतन्त्रता का वर्ष कहा जाता है जिसमें 17 देश स्वतन्त्र हो गए। इसके बाद एक-एक करके अफ्रीका के शेष देश भी स्वतन्त्र हो गए और आज केवल इनेगुये प्रदेशों को छोड़कर सम्पूर्ण अफ्रीका महाद्वीप आजाद हो चुका है। जो देश स्वतन्त्र हुए वे ये हैं—

क्र.सं.	नाम देश	स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासकीय देश	स्वतन्त्र होने की तिथि
1.	लाइबेरिया	अमेरिका	1847
2.	इथियोपिया	—	1941
3.	धीबिया	—	24 नवम्बर 1951
4.	इरिट्रिया	इटली	सितम्बर 1952
5.	सूडान	ब्रिटेन	जनवरी 1956
6.	मोरक्को	फ्रांस	मार्च 1956
7.	ट्यूनीशिया	फ्रांस	मार्च 1956
8.	घाना	ब्रिटेन	मार्च 1957
9.	गिनी	फ्रांस	अक्तूबर 1958
10.	संयुक्त अरब गणराज्य	—	1959
11.	कैमरून	फ्रांस	जनवरी 1960
12.	मोरक्को (कुछ अंश)	स्पेन	मार्च 1960
13.	टोगा	फ्रांस	अप्रैल 1960
14.	मालीसघ	फ्रांस	जुलाई 1960
15.	कांगो गणराज्य	बेल्जियम	जुलाई 1960
16.	सोमालिया	ब्रिटेन व इटली	जुलाई 1960
17.	मालागासी गणराज्य	फ्रांस	जुलाई 1960
18.	छाड	फ्रांस	अगस्त 1960
19.	नाइजर	फ्रांस	अगस्त 1960
20.	आइवरी कोस्ट	फ्रांस	अगस्त 1960
21.	बोल्डाई गणराज्य	फ्रांस	अगस्त 1960
22.	गैबेन	फ्रांस	अगस्त 1960
23.	होमी	फ्रांस	अगस्त 1960
24.	कांगो गणराज्य	—	अगस्त 1960
25.	मध्यवर्ती अफ्रीका	—	अगस्त 1960
26.	नाइजीरिया	ब्रिटेन	अक्तूबर 1960
27.	मारितानिया	फ्रांस	नवम्बर 1960
28.	सियेरालियोन	फ्रांस	अप्रैल 1961
29.	रूण्डा-उरुंडी	बेल्जियम	जुलाई 1962
30.	मलजीरिया	फ्रांस	सितम्बर 1962
31.	युगांडा	ब्रिटेन	अक्तूबर 1962
32.	तांगानिका	ब्रिटेन	दिसम्बर 1962
33.	केनिया	ब्रिटेन	दिसम्बर 1963
34.	जंजीबार	ब्रिटेन	दिसम्बर 1963

क्र.सं.	नाम देश	स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासकीय देश	स्वतन्त्र होने की तिथि
35	न्यासालैण्ड (मलावी)	ब्रिटेन	1964
36.	जेम्बिया (उत्तरी रोडेशिया)	ब्रिटेन	1964
37	गैम्बिया	ब्रिटेन	1965
38	ब्रिटिश गियाना (नया नाम गुयाना)	ब्रिटेन	मई 1966
39	बोत्सवाना (बच्चूआनालैण्ड)	ब्रिटेन	सितम्बर 1966
40	लेसोथो वसुतोलैण्ड	ब्रिटेन	अक्टूबर 1966
41.	बारबाडोस	ब्रिटेन	नवम्बर 1966
42.	मारिशस	ब्रिटेन	मार्च 1968
43.	ग्रेनाडा	ब्रिटेन	फरवरी 1974
44	गिनी बिसाऊ	पुर्तगाल	सितम्बर 1974
45.	मोजाम्बिक	पुर्तगाल	जून 1975
46.	केपवर्दे	पुर्तगाल	जुलाई 1975
47.	कोमोरी द्वीप समूह	पुर्तगाल	जुलाई 1975
48	अंगोला	पुर्तगाल	नवम्बर 1975
49.	सेशेल्स	ब्रिटेन	जून 1976
50.	जिबाब्वे (रोडेशिया)	ब्रिटेन	अप्रैल 1980
51.	बेलीज	ब्रिटेन	सितम्बर 1981
52.	आण्टिगुआ	ब्रिटेन	अक्टूबर 1981

अफ्रीका महाद्वीप की राजनीतिक परम्पराएँ आरम्भ से ही अधिनायकवादी और सर्वसत्तावादी रही हैं। औपनिवेशिक युग शुरू होने से पहले अफ्रीका महाद्वीप में एकतन्त्रात्मक शासन का बोलबाला था। कबीलों के भरदार स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करते थे। औपनिवेशिक युग के दौरान भी इस स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। अफ्रीका के लोग साम्राज्यवादी शक्तियों के निरंकुश शासन से पीड़ित रहे। अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में स्वस्थ लोकतन्त्रीय परम्पराओं का विकास नहीं हो सका। अब स्वतन्त्रता के इस युग में अनेक अफ्रीकी देशों में—विशेषकर भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों में ससदीय लोकतन्त्र की स्थापना की गई है। यद्यपि उदार लोकतन्त्र अभी अधिक सफल नहीं हुआ है, तथापि अफ्रीका धीरे-धीरे लोकतान्त्रिक परम्पराओं और संस्थाओं के विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है। कुछ देशों में लोकतन्त्र काफी आगे बढ़ा है तो कुछ देशों में निर्वाचित एकतन्त्र की स्थापना की गई है।

अफ्रीका में साम्यवाद का प्रभाव अभी तक विशेष उग्र नहीं हो पाया है। अफ्रीकी देशों के प्रति सोवियत मध्य और चीन के दृष्टिकोण भिन्न रहे हैं। सोवियत मध्य ने अफ्रीकावासियों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध मध्य में नैतिक और नूतनीतिक समर्थन दिया है जबकि चीन की नीति अफ्रीकी देशों पर दबाव डालने और उन्हें

अपनी शक्ति से आतंकित करने की रही है। यद्यपि दोनों ही देश चाहते हैं कि अफ्रीका में साम्यवाद का प्रसार हो, तथापि दोनों के ढंग भिन्न-भिन्न हैं। दोनों ही देशों के नेता अफ्रीका के विभिन्न देशों के दौरे करते रहे हैं।

राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर भी अफ्रीका के सामने एक बड़ी विवट समस्या अपनी इस स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने की है। महाशक्तियाँ और कुछ अन्य बड़े देश अफ्रीका के पिछड़े देशों को अपने प्रभाव में लाने की उत्सुक हैं। आर्थिक दृष्टि से अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ है, यद्यपि प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से वह समृद्ध है। अफ्रीका के देश चाहते हैं कि विभिन्न राष्ट्र उन्हें आर्थिक और प्राविधिक सहायता दें ताकि वे अपने प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर सकें, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उनकी सम्पन्नता और स्वतन्त्रता पर कोई आंच न आए। अब यह सम्भव नहीं है कि अफ्रीकी देश वाश्चात्य औद्योगिक उत्पादन के लिए बाजार बन कर रह जाएँ।

एशियायी राष्ट्रों की तरह ही अफ्रीकी राज्य भी पारस्परिक फूट के शिकार हैं। विभिन्न राज्यों में पारस्परिक कलह का बोलबाला रहता है, कई बार सैनिक भड़पें भी होती हैं। सैनिक क्रान्तियाँ होना भी एक आम बात है। पृथक्तावादी आन्दोलन भी जब तब जोर पकड़ते हैं। शिक्षा, सम्पत्ता और विज्ञान में पिछड़े हुए होने के कारण अफ्रीका के देशों में राष्ट्रवाद अभी इतना प्रभावशाली नहीं हो सका है जितना एशिया महाद्वीप में। ये सब बातें अफ्रीका महाद्वीप की एकता के लिए हानिकर हैं और इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर अफ्रीका का इतना शक्तिशाली चित्र अभी उभर नहीं सका है जितना उभरना चाहिए था। भविष्य में अफ्रीका के कुछ देशों में साम्यवादी आन्दोलन के जोर पकड़े आने और स्थिति विस्फोटक बन जाने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अफ्रीका के कई देशों जैसे काहिरा, अदिस अबाबा, प्रोटेरिया, मोनरोविया आदि में साम्यवादियों के कूटनीतिक ग्रहण हैं। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रीका में स्थानीय साम्यवादी दलों का प्रभाव है। वैसे अफ्रीका के नेताओं में से बहुत कम ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं।

एकता की भावना आज भी एक सक्रिय तत्त्व

उन तमाम विभाजनों के बावजूद जो अफ्रीकी देशों को विभिन्न समूहों में बाँटते हैं (अरब या मुस्लिम देश ब्रितानी-राष्ट्रमण्डल आदि)। अफ्रीकी एकता की यह भावना यूरोप के साथ सम्पर्क का फल नहीं है। राजनीतिक स्वतन्त्रता के आन्दोलनों से भी इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है और न कुछ अफ्रीकी देशों में प्रभावी मार्क्सवादी राजनीति से ही है। अफ्रीका में एकता की भावना पहले से ही विद्यमान है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आन्दोलनों और उनके नेताओं द्वारा केवल उनके उपयोग की चेष्टा होती नहीं है। मंगोला, रोडेजिया या दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका के प्रश्न अगर सम्पूर्ण अफ्रीका को आन्दोलित कर देते हैं, अथवा कांगो या नाइजीरिया में पृथक्तावादी आन्दोलनों को अगर समस्त अफ्रीका के भावात्मक विरोध का सामना करना पड़ता है तो इसलिए नहीं कि ये प्रश्न प्राधुनिकता या

आर्थिक विकास से जुड़े हैं, वरन् इसलिए कि इतिहास, संस्कृति और सामाजिक सम्बन्धों में अफ्रीकी एवता की भावना एक जीवन्त तत्त्व है।

स्वाधीनता की इन्तजार वाले देश

अगस्त 1981 के दिनमान में श्री त्रिलोकदीप का एक लेख 'स्वाधीनता की इन्तजार वाले देश' प्रकाशित हुआ था जिससे हमें वर्तमान में अवशिष्ट राजनीति-भौगोलिक उपनिवेशवाद का पता चलता है। श्री त्रिलोकदीप का चित्रण इस प्रकार है—

लगभग साढ़े चार अरब की आबादी वाली दुनिया में आज भी तीस-एक देश (इनमें हजारों की तादाद में फँसे छोटे द्वीप शामिल नहीं) ऐसे हैं जो स्वाधीनता के लिए कसम खा रहे हैं। आज भी वे उपनिवेश हैं। कई उपनिवेश भ्रान्तिपूर्ण ढंग से परस्पर वार्ता द्वारा अपने भूतपूर्व शासकों को समय की हवा में अवगत कराने में सफल हो जाते हैं और स्वाधीनता प्राप्त कर लेते हैं तो कइयों को मध्यम का रास्ता अस्विकार करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी उपनिवेश हैं जो संयुक्तराष्ट्र की धरोहर हैं और उन्हें न्याय क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है लेकिन न्याय क्षेत्र वाले सभी देशों को आज्ञादी मिल ही जानी हो यह जरूरी नहीं। कुछ ऐसे भी उपनिवेश हैं—खाम तौर पर छोटे-छोटे द्वीप—सुरक्षा या प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण अपनी औपनिवेशिक स्थिति में ही संतुष्ट हैं। उन्हें शायद एक तो अपने छोटे और कमजोर होने का सदैव अहसास रहता है और दूसरे साधनों की कमी की यथोचित जुगाड़ न कर पाने के कारण पड़ोसी देशों की ललचाई नजरे उनके अस्तित्व के लिए किसी समय भी खतरा बन सकती है।

इस ढाँचे को ढाल बना कर जब हम विश्व की स्थिति का सर्वेक्षण करते हैं तो पाते हैं कि आज भी औपनिवेशिक शक्तियाँ मोटे तौर पर वही हैं जो आज से कुछ सदियों पहले थी अर्थात्, फ्रान्स, पुर्तगाल, हॉलैण्ड, स्पेन, बेल्जियम आदि। अन्वत्ता अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इस सूची में ओग जुड़ गये हैं जिनका प्रभाव क्षेत्र शुद्ध औपनिवेशिकता की दृष्टि से उतना व्यापक नहीं, जितना कि ब्रिटेन और फ्रान्स जैसे देशों का रहा है। आज भी प्रशान्त मागज, कॅरेबियाई द्वीप-समूह में तमाम ऐसे छोटे-बड़े द्वीप छिपे पड़े हैं जो आज्ञादी की बाट जोह रहे हैं। ब्रिटेन फ्रान्स ने इन उपनिवेशों को स्वाधीनता प्रदान करने की एक नियोजित और लगभग निश्चित रूपरेखा या पैमाना तैयार कर रखा है यानी पहले आन्तरिक स्वायत्तता (विदेश, अर्थ और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के प्रतिरिक्त) प्रदान कर स्थानीय नेताओं की प्रशासनिक और राजनैतिक क्षमता का अध्ययन करने और संतुष्ट हो जाने पर उन्हें स्वाधीनता प्रदान करना। यदि कोई देश मध्यम या रास्ता अपनाता है तो भी परस्पर वार्ता और उचित दस्तावेजों द्वारा उसे स्वाधीनता प्रदान करने का भी प्रयास होता है, जैसे जिम्बाब्वे (18 अप्रैल 1980) यद्यपि उसके गोरे नेता इयान स्मिथ ने दस वर्ष पूर्व ही एकतरफा स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। आज भी विश्व में मुक्ति मंथन के अनेक मोर्चे गरम हैं। यद्यपि

अंगोला, जिंबाब्वे, मोजाम्बिक के मुक्ति संग्रामी अपने-अपने देशों को स्वाधीन कराने में सफल रहे हैं तथापि नामीबिया की स्वाधीनता प्राप्ति का सपना लम्बा ही सिबना चला जा रहा है। वास्तव में नामीबिया इतना खनिजसम्पन्न है कि दक्षिण अफ्रीका उसकी स्वाधीनता में निरन्तर रुद्धचने डाल रहा है। वोह निर्यात करने वाले देशों में उसका चौथा स्थान है। विश्व के हीरो का लगभग 16 प्रतिशत तथा यूरेनियम का लगभग तीन प्रतिशत उत्पादन नामीबिया में होता है। इनके अलावा सोना, ताम्र, ताँबा, जस्ता और सम्भवतया तेल भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। लिहाजा दक्षिण अफ्रीका को यह भी चिन्ता है कि एक बार नामीबिया के स्वाधीन हो जाने से उसकी अपनी गोरी अल्पमत सरकार को खतरा पैदा हो सनता है जिस प्रकार जिंबाब्वे के अल्पसंख्यकों को हुआ था।

नामीबिया का क्षेत्रफल फ्रान्स और इटली को मिलाकर भी अधिक है। 1966 में संयुक्तराष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर उस पर दक्षिण अफ्रीका साम्राज्य समाप्त कर दिया था। उसी समय कुछ देशों ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक नाकेबन्दो की भी माँग की थी। इस प्रस्ताव से नामीबिया के दक्षिण-पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन (स्वापो) को बल मिला। उसे स्वाधीन नामीबिया के तौर पर प्रतिष्ठित किया गया। 1973 में संयुक्तराष्ट्र ने भी 'स्वापो' को नामीबिया का वास्तविक प्रतिनिधि माना और उसके नेता संमनुजोमा को सुना भी गया। बावजूद संयुक्तराष्ट्र के प्रस्ताव के दक्षिण अफ्रीका का बड़ा रुत बरकरार है। 1978 में अलबत्ता, पाँच पश्चिमी देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, पश्चिमी जर्मनी और कनाडा) ने एक 'सम्पर्क गुट' का गठन किया। इन देशों में अफ्रीका के प्रग्रिम पक्ष के देशों के नेताओं से भी नामीबिया के भविष्य के बारे में बातचीत की। सभी पार्ताओं के फलस्वरूप नामीबिया की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की। उस योजना में युद्धविराम, संयुक्तराष्ट्र की देखरेख में मुक्त चुनाव तथा नामीबिया और अंगोला के बीच विसंख्यीकृत खण्ड की स्थापना की व्यवस्था थी जहाँ पर संयुक्तराष्ट्र शान्ति सैनिक नियुक्त किये जाने का प्रावधान था। संयुक्तराष्ट्र वाल्विस खाड़ी को भी नामीबिया का भाग मानता है। दक्षिण अफ्रीका सहित सभी देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया लेकिन जब चुनाव कराने का अवसर आया तो दक्षिण अफ्रीका मुकर गया।

20वीं सदी के शुरू में ऐसा लगता था कि आधी से अधिक दुनिया के पँरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के समय विश्व के 50 प्रतिशत क्षेत्र की 31.5 प्रतिशत आबादी गुलाम थी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र अर्द्ध-औपनिवेशिक स्थिति में थे। इसे मिलाकर 72 प्रतिशत क्षेत्र की 31.5 प्रतिशत जनसंख्या औपनिवेशिक और अर्द्ध-औपनिवेशिक स्थिति में थी। 1905 में सोवियत संघ में जारशाही के विरुद्ध शान्ति से लगता है कि लोगों को दिशा दी और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फासीवाद की पराजय के बाद औपनिवेशिक प्रणाली बालू के टीले की तरह ढहने लगी। यद्यपि एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में औपनिवेशिक बस्तियाँ अधिक थी तथापि विश्वयुद्ध के बाद स्वाधीनता की लहर एशिया में अधिक तेज थी। उस दौर में

भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, बर्मा, चीन, श्रीलंका स्वाधीन हुए। उस समय सर विंस्टन चर्चिल ने दावा किया था कि वे ब्रितानी हुकूमत का उन्मूलन होते नहीं देख सकते। बावजूद इसके उनके जीते जी अनेक देशों में युनियन जंक के स्थान पर वहाँ का स्थानीय ध्वज फहराया था।

एशियाई देशों की जागरूकता ने अफ्रीकियों को भी उद्वेलित किया। लिहाजा 1950 के बाद मोरक्को, मूडान, घाना और गिनी आजाद हुए। 1960 को 'अफ्रीकी वर्ष' कहा जा सकता है। 1960 और 1970 के बीच सत्रह देशों ने स्वाधीनता प्राप्त की। अफ्रीका में फ्रांस और बेल्जियम की बस्तियाँ थी, लिहाजा इन देशों की आजादी से उनका बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र समाप्त हो गया। 1960 में ही संयुक्तराष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर सभी ध्वे हुए उपनिवेशों और वहाँ के लोगों को स्वाधीनता प्रदान करने का आह्वान किया। इस घोषणापत्र के जारी होने के बाद 55 देश आजाद हुए। इनमें 24 अफ्रीका के, 7 एशिया के, दस लातीनी अमेरिका के, एक यूरोप का तथा नौ सागरी देश थे। इनमें 14 करोड़ की आबादी है और क्षेत्रफल एक करोड़ वर्ग किलोमीटर था। संयुक्तराष्ट्र की मदद से मग्या 1980 में 1945 के के मुकाबले तिगुनी हो गई। 12 दिसम्बर 1980 को संयुक्तराष्ट्र ने अपने उनी घोषणापत्र की 20वीं बर्रगाँठ पर औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा संयुक्तराष्ट्र के घोषणापत्र पर आचरण करने के कार्य की सराहना की।

बावजूद उपनिवेशवाद उन्मूलन की इस प्रक्रिया के आज भी तीस लाख (विश्व जनसंख्या का 0.3 प्रतिशत और क्षेत्रफल का एक प्रतिशत) से अधिक लोग स्वाधीनता का इन्तजार कर रहे हैं। नामीबिया के अतिरिक्त पश्चिमी सहारा (स्पानी बस्तो) और पूर्वी तिमोर (पुर्तगाली उपनिवेश) खामे चर्चित क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी राष्ट्रीय मुक्ति सपर्यं जोरो पर है। संयुक्तराष्ट्र और अफ्रीकी एगता संगठन ने पश्चिमी सहारा के भविष्य का दावित्व वहाँ के लोगों को सौंपा है। यद्यपि उमके भारतानिया और मोरक्को दोनों दावेदार हैं और मोरक्को ने उस पर बलात् बढ्का कर रखा है। 11 नवम्बर 1980 को संयुक्तराष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर मोरक्को से पश्चिमी सहारा पर अपना बढ्का समाप्त कर पोलिसारियो मोर्चे से सीधे बातचीत का आग्रह किया। जहाँ तक पूर्वी तिमोर का सम्बन्ध है पुर्तगाल ने जून, 1974 को पूर्वी तिमोर सश्रित सभी बस्तियों को स्वाधीन करने का निरुण्ड निर्या था। 1976 में इंडोनेशिया ने पूर्वी तिमोर पर बढ्का कर उसे अपना 27वा प्रान्त घोषित कर दिया। पूर्वी तिमोर की आजादी के लिए फ्रेन्चिनीनो स्वाधीनता संग्रामी सश्रिय है। संयुक्तराष्ट्र ने पूर्वी तिमोर के लोगों के भी आत्म-निर्णय के अधिकार को स्वीकार किया है और फ्रेन्चिनीनो से बातचीत करने का परामर्श दिया है जिसके लिए इंडोनेशिया तैयार नहीं।

संयुक्तराष्ट्र की एक विशेष समिति प्रतिवर्ष स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आतुर उपनिवेशों के बारे में अपनी रपट महासभा को देती है। 1980 की रपट में नामीबिया, पश्चिमी सहारा, पूर्वी तिमोर के अलावा कुछ अन्य छोटे देशों का भी ज़ापर जा किया गया। इनमें पश्चिमी प्रशान्त में स्थित माइक्रोनेशिया नामक एक

स्थान है जिसके अन्तर्गत 2100 द्वीप आते हैं। यह अमेरिका की एक बस्ती है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व माइक्रोनेशिया जापान का उपनिवेश हुआ करता था। माइक्रोनेशिया में ही महायुद्ध के समय अमेरिकी-जापानी नौसैनिक लड़ाई हुई थी। यहाँ के कुछ द्वीपों में अमेरिका अपने परमाणु परीक्षण भी करता रहता है। इसके अलावा अमेरिकन समोआ और गुलाम की सम्पत्तियों पर भी संयुक्तराष्ट्र महामभा में विचार-विमर्श हुआ। एक प्रस्ताव द्वारा महासभा ने यहाँ के लोगों की अपनी स्वाधीनता के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। महासभा की यह भी मान्यता थी कि यहाँ स्थित सैनिक अट्टे स्वाधीनता के छोड़े आते हैं जिसका रास्ता ढूँढा जाना चाहिए।

कुछ ऐसे भी गैर-स्वशासी क्षेत्र हैं जो आकार और संख्या दोनों में बहुत छोटे हैं। हिन्दमहासागर में स्थित कोकास-कोलिंग द्वीप की आबादी केवल 490 है जबकि प्रशान्त में स्थित पिटकैरेन द्वीप की आबादी मात्र 60 है। इनके अलावा बहुत से निर्जन द्वीप हैं। कुछ ऐसे द्वीप भी हैं जहाँ पर केवल कुछ खानाबदोश ही रहते हैं। लेकिन इन निर्जन द्वीपों का भी अपना महत्त्व है। औपनिवेशिक शक्तियाँ इन निर्जन द्वीपों को हवाई अड्डों, सैनिक भण्डारागारों, नए किस्म के अस्त्रों और परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान मानती हैं। यद्यपि आज उपनिवेशवाद का जमाना नहीं और संयुक्तराष्ट्र ने विभिन्न मंचों पर उसके विरुद्ध आवाज भी बुलन्द की है बावजूद इसके बड़े देश एकतरफ अपनी आर्थिक दृष्टि से और दूरी तरफ राजनीतिक, सैनिक तथा सामरिक दृष्टि से इन छोटे-छोटे द्वीपों को अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए कोई न कोई बहाना ढूँढ लेते हैं। आज भी ब्रिटेन के अधीन सबसे अधिक बस्तियाँ हैं। यद्यपि धीरे-धीरे उन्हें स्वाधीनता प्रदान की जा रही है, बावजूद इसके कुछ ऐसे उपनिवेश हैं जिन्हें वह आसानी से स्वाधीनता प्रदान नहीं करना चाहता। इनमें जिब्राल्टर, बरमुडा, बरूनी, हाँगकाँग, वेतीज, फाकलैण्ड आदि क्षेत्र आते हैं। वेतीज जो मेक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच विवाद का कारण रहा है और अब भी बना हुआ है उसे 21 सितम्बर, 1981 को स्वाधीनता प्रदान की गई। लेकिन बरमुडा, जिब्राल्टर आदि को स्वाधीन करने के बारे में ब्रिटेन के दृष्टिकोण को व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। जिब्राल्टर के बारे में स्पेनी रूब की वजह से ही स्पेन के मन्त्राट हुआन कार्लोस ने युवराज चार्ल्स के शाही विवाह का बहिष्कार किया था।

जहाँ तक हाँगकाँग का सम्बन्ध है यह शाही बस्ती ब्रिटेन ने 99 वर्ष के पट्टे पर चीन में ली है। यह पट्टा 1997 में समाप्त होगा। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 391 वर्गमील है और आबादी 42 लाख 50 हजार (1974 का आँकड़ा)। यहाँ पर लगभग 20 हजार अंग्रेज भी रहते हैं। 1949 से 1962 और अब 1979 में भी काफी बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने हाँगकाँग में पनाह ली।

यहाँ के प्रमुख उद्योगों में जहाज निर्माण, कपड़े के कारखाने, लोहा और इस्पात, चीनी मत्तय उद्योग आदि हैं। ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों की सबसे अधिक रुचि यहाँ से चीनी गतिविधियों पर नज़र रखना है। हिन्दमहासागर में स्थित मारिशस

और जेसल्स तो स्वाधीन हो चुके हैं लेकिन चागोस द्वीप समूह, जिसमें विवादास्पद दियागो गार्सिया द्वीप भी शामिल है, को स्वाधीन करने के लिए ब्रिटेन तैयार नहीं। दियागो गार्सिया को उसने अमेरिका को बेच दिया है और वहाँ पर अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियाँ बड़ी तेजी से हिन्दमहासागर में निरन्तर बढ़ रही हैं। सबसे अधिक उपनिवेश प्रशान्त सागर में स्थित है और ये सभी छोटे-छोटे द्वीप सारे सागर में बिखरे पड़े हैं जैसा कि निम्न तालिका में स्पष्ट है—

अन्तिम उपनिवेश

ब्रितानी प्रशासन के अन्तर्गत

- बहनी (जनसंख्या 2,13,000, क्षेत्रफल 2,226 वर्गमील)
- बेसीज (जनसंख्या 1,50,000, क्षेत्रफल 8,866 वर्गमील, राजधानी बेलमोपान, 21 सितम्बर, 1981 को स्वाधीन हो गया)
- जिब्राल्टर (जनसंख्या 30,000)
- वरमुदा (जनसंख्या 60,000, राजधानी हैमिल्टन)
- फाकलैण्ड (माल्दीनास) द्वीप (जनसंख्या 2,000, क्षेत्रफल 4619 वर्गमील)
- ग्राटिगुआ (जनसंख्या 70,000, क्षेत्रफल 171 वर्गमील, राजधानी सेटजान) (31 अक्टूबर, 1981 को स्वाधीन हो गया)
- पिटकैरन द्वीप (जनसंख्या 60, क्षेत्रफल 18 वर्गमील)
- ब्रिटिश बर्जिन द्वीप (जनसंख्या 12,000)
- टक्स और कायकोस द्वीप (जनसंख्या 7,000, क्षेत्रफल 166 वर्गमील, राजधानी-गैड टर्क)
- कमान द्वीप (जनसंख्या 14,000, क्षेत्रफल 93 वर्गमील, राजधानी जार्ज टाउन)
- माटसेराट (जनसंख्या 13,000, क्षेत्रफल 33 वर्गमील)
- सेंट हेलेना (जनसंख्या 6,000, क्षेत्रफल 1200 मील, राजधानी जेम्स-टाउन)

अमेरिकी प्रशासन के अधीन

- प्वर्तोरिका (आबादी 33 लाख, 1952 में अमेरिका ने इसे गैर-स्वशासित क्षेत्रों की सूची से निकाल दिया, बावजूद इसके आज भी प्वर्तोरिको को अमेरिका का 51वाँ राज्य माना जाता है)
- प्रशान्त द्वीप (मारियाना, मार्शल और कारोलाइन द्वीप, जनसंख्या 1,30,000)
- पूर्वी समाग्रो (जनसंख्या 30,000)
- गुआम (जनसंख्या 1,05,000)
- अमेरिकन बर्जिन द्वीप (जनसंख्या 1,00,000)

आस्ट्रेलिया के तहत

- कोकोस या कीलिंग द्वीप (जनसंख्या 490, क्षेत्रफल 5 वर्गमील)

न्यूजीलैण्ड के तहत

टोकेलाउ द्वीप (जनसंख्या 2000, क्षेत्रफल 4 वर्गमील)

कुक द्वीप (जनसंख्या 21,000, क्षेत्रफल 93 वर्गमील)

नितु द्वीप (जनसंख्या 6000, क्षेत्रफल 100 वर्गमील)

फ्रांस के विदेश विभाग के अन्तर्गत

गुआदेलू (जनसंख्या 3,25,000, क्षेत्रफल 687 वर्गमील, राजधानी बसे-सेरे)

मार्टीनी (जनसंख्या 3,25,000, क्षेत्रफल 426 वर्गमील, राजधानी फोर्ट द-फ्रांस)

फ्रांसीसी गयाना (जनसंख्या 70,000, क्षेत्रफल 37,740 वर्गमील, राजधानी कोयेन)

सेंट पियरे और मिकेलोन द्वीप (जनसंख्या 5,800, दोनों द्वीपों का क्षेत्रफल 94 वर्गमील, राजधानी सेंट पियरे)

रियूनियन (जनसंख्या, 5,00,000, क्षेत्रफल 969 वर्गमील, राजधानी सेंट डेनिस)

मायोटे : पहले कौमोरो का भाग । 1976 में फ्रांस के विदेश विभाग के तहत क्षेत्रफल 11 वर्गमील और जनसंख्या 51,800 ।

फ्रांसीसी क्षेत्र

न्यू कैलेडोनिया (जनसंख्या 19,40,000, क्षेत्रफल 1,115 वर्गमील, राजधानी नोमिया)

फ्रांसीसी पोलिनेशिया (जनसंख्या 1,40,00 क्षेत्रफल 1,544 वर्गमील)

वालिस और फुतुना द्वीप (जनसंख्या 10,000, क्षेत्रफल 106 वर्गमील)

स्पेन के प्रशासन में

उत्तरी गोरारको मे बूटाना और मोलिल्ला (जनसंख्या 1,30,000)

डच प्रशासन में

डच अंटिल्स (जनसंख्या 2,40,000, क्षेत्रफल 395 वर्गमील, राजधानी विलेग-स्टेड)

दूसरी महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस रहा है । फ्रांस का दबदबा अफ्रीकी देशों पर अधिक था लेकिन 1960 से 1980 के बीच अधिकतर अफ्रीकी देशों के स्वाधीन हो जाने के बाद अब उसका नियन्त्रण कुछ इनेगिने स्थानों तक ही सिमट कर रह गया है । कुछ स्थानों को तो फ्रांस अपने विदेश विभाग के अन्तर्गत मानता है जबकि कुछ को वे उपनिवेश या क्षेत्र मानते हैं । रियूनियन, गुआदेलू, मार्टीनी, सेंट पियरे, फ्रांसीसी गयाना उसके विदेश विभाग में आते हैं जबकि फ्रांसीसी पोलिनेशिया, न्यू कैलेडोनिया, वालिस और फुतुना द्वीप उसकी वस्तियों में माने जाते हैं । इन सभी वस्तियों की स्थिति का आकलन संयुक्तराष्ट्र की विशेष समिति ने भी किया है और पूरे अध्ययन के बाद वहाँ के लोगों की स्थिति से इन

औपनिवेशिक शक्तियों को सूचित भी किया है। पिछले दिनों फ्रांस और कोमोरो की सरकार के बीच मायोटे द्वीप के प्रश्न पर तनाव पैदा हो गया। दोनों ही मायोटे पर अपना-अपना दावा जतला रहे हैं। यह मसला भी संयुक्तराष्ट्र के विचाराधीन है।

बहरहाल, लगभग तीस-एक ऐसे देश हैं जो अभी स्वाधीनता प्राप्त करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। कुछ देशों के मुक्ति संग्रामी अपने देशवासियों की आवाज लोगों तक पहुँचाने में समर्थ हो जाते हैं तो कभी संयुक्तराष्ट्र की विशेष समिति के प्रतिनिधि यहाँ के लोगों की इच्छाओं से विश्व निकाय को अवगत कराते रहते हैं। लेकिन ये बड़ी शक्तियाँ जो इन देशों से प्राप्त कच्चे माल को पक्का बना कर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किए हुए हैं, आसानी से उन्हें अपने जंगल में निकालने के लिए तैयार नहीं। केवल उम्मीद ही की जा सकती है कि वर्तमान शासक अपने पुरखों की पुरानी बस्तियों को उनकी यादगार के तौर पर नहीं महजेंगे बल्कि स्वाधीन करके अपने आधुनिक, रचनात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण का यथेष्ट परिचय देंगे।

स्वतन्त्र अफ्रीका-महाद्वीप की समस्याएँ

(Problems of Independent African Continent)

नवोदित अफ्रीका के राज्यों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से अधिक समस्याएँ तो यहाँ की पिछड़ी हुई आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न होती हैं। यहाँ के देशों के सामने विश्व के अन्य देशों के समरक्ष धाने के लिए एक लम्बा रास्ता पार करने को पड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यहाँ के कुछ देशों में शान्ति हुई, गृह-युद्ध छिड़े तथा जातीय भेद-भाव के आधार पर अनेकों उपद्रव हुए। महाद्वीप के देशों में विकास के लिए आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता का सूत्रपात हुआ। उनके हित राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर परस्पर टकराने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तरों पर सर्वोच्चता पाने के लिए यहाँ के विभिन्न देशों के बीच शक्ति-मंथन छिड़ गया। इस प्रकार स्वतन्त्र अफ्रीका में अनेकता, मंथन और प्रतियोगिता का वातावरण जोर पकड़ने लगा। यहाँ के राष्ट्रों के विकास के लिए परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की प्रमुख आवश्यकता है, किन्तु यहाँ इसके विपरीत प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही हैं। विश्व की अन्य शक्तियाँ इस फूट का लाभ उठा रही हैं। साम्यवादी गुट तथा पश्चिमी देश दोनों ही अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयत्नों में सफल हैं। यूरोप के जिन देशों ने अफ्रीका के अपने उपनिवेशों को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी है वे भी यहाँ किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव जमाए रखना चाहते हैं। उनका हित इस बात में है कि इन देशों पर गहरी जानि का ही प्रमुख कायम रहे। स्वतन्त्र अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख समस्याएँ निम्नीकित हैं—

(1) अफ्रीका-महाद्वीप में मिली-जुली समस्याओं तथा विचारों के बल पर शान्ति को गफलत बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें एक नवीन अफ्रीका की सम्भावना निहित है किन्तु नवीन विचारों एवं संस्थाओं का यह प्रयोग अफ्रीका के पुगने रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं में भिन्न है तथा इसके प्रति यहाँ के लोगों में

विरोधी भावनाएँ हैं। समाज के परम्परावादी रूप के विलोप से जो अमरुक्षा की भावना पैदा होती है वह इन देशों के विकास-मार्गों की सफलता में मुख्य रूप से बाधक है।

(2) विकास-कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अफ्रीका-महाद्वीप में पहले सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति होना जरूर आवश्यक है। यहाँ के धार्मिक नियम, राजनीतिक विचार, अनुशासनहीनता की प्रवृत्तियाँ, आदि में मूलभूत परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। हो सकता है कि इस परिवर्तन-काल में यहाँ के देशों को अनेक हिंसात्मक तथा नृशंखतापूर्ण कार्य भी करने पड़ें।

(3) अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महत्त्व जानने से पूर्व यह समझना उपयोगी है कि यहाँ की क्रांति का लोगों के जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। स्वतन्त्रता से पूर्व यहाँ के लोगों पर हजारों मील दूर बैठे शासकों के आदेशों से शासन होता था। उपनिवेशवादी शक्तियों के प्रतिनिधि ही यहाँ के सब कुछ थे। उनके साथ अफ्रीकावासियों का सेवक और स्वामी का सम्बन्ध था, किन्तु अब यह स्थिति नहीं रही है, तो भी जातीय उच्चता के आधार पर यूरोप के देश इन देशों पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित किए हुए हैं।

(4) गोरे और काले का भेद प्रकृति से उत्पन्न होता है। यह मनुष्यवृत्त नहीं है और न ही मनुष्य इसे परिवर्तित कर सकता है किन्तु यह रंग-भेद अफ्रीका के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक शक्तिशाली तत्त्व है। गुन्थर (Gunther) के अनुसार, "सब चीजों से ऊपर रंग-भेद ही है जो अफ्रीका में प्रसक्तोप तथा विद्रोह उत्पन्न करता है। यह अफ्रीकी हीनता का प्रधान कारण है जिससे उपद्रव और विद्रोहों का भूतपात होता है और गोरे तथा काले दोनों ही प्रकार के लोगों के मस्तिष्क को विवृत कर देता है।" यूरोपीय शासन काल में जातीय तथा रंग पर आधारित भेद-भाव की नीति को पर्याप्त बढ़ावा दिया गया था। रंग-भेद के कारण पूरे महाद्वीप में ही एक प्रकार की गहरी खाई पड़ गई थी तथा जिन देशों में यूरोपीय लोग नहीं रहते, वहाँ के काले लोग भी अपने आपको गोरो से हीन मानते हैं। यह खाई अब तक बनी रहेगी जब तक चमडी के गोरेपन के आधार पर अधिकांश जन-समुदाय के विरुद्ध थोड़े से लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होते रहेगें। जॉन हच (John Hatch) के शब्दों में, "अफ्रीका के लोग आत्म-विश्वास, जो सहिष्णुता के लिए आवश्यक होता है, अब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे रंग के आधार पर किए जाने वाले भेद-भाव से अपने आपको मुक्त नहीं कर लेते।" धीरे-धीरे अफ्रीका के देशों में अब अफ्रीकियों की सरकारें स्थापित होती जा रही हैं तथा अब गोरे लोगों के विरुद्ध काले लोगों को कुछ विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति घर करती जा रही है।

(5) केवल रंग-भेद तथा जाति-भेद को समाप्त कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अफ्रीका के देशों में यूरोपीय देशों द्वारा अनेक मूलभूत परिवर्तनों की स्थापना करके

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को बदल दिया गया था। अफ्रीका में शान्ति को पूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इस शान्ति को सामाजिक तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लाया जाए। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद इन देशों में जो सरकारें स्थापित की गई हैं, यद्यपि उनका संचालन देश के निवासियों द्वारा ही किया जाता है, तथापि वे उतने ही अधिक सत्ता एवं अधिकार का प्रयोग करती हैं जितना विदेशियों द्वारा किया जाता था।

अनेक अफ्रीकी देशों में एकदलीय व्यवस्था को अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया। इस मान्यता पर अफ्रीका के आदिवासी जीवन का प्रभाव है। आदिवासी जीवन की सामान्य परम्परा के अनुसार विरोधी का संगठित होना अनुचित है क्योंकि यह अनेक प्रकार के झगड़े उत्पन्न करता है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर सभी व्यक्तियों के मतों का प्रभाव रहता है। आज एक सामान्य अफ्रीकी अपने जीवन में यह महसूस करता है कि उसके ऊपर सत्ता की जिस मात्रा का स्वतन्त्रता के बाद में प्रयोग किया जा रहा है वह स्वतन्त्रता के पूर्व प्रयोग की जाने वाली मात्रा से बड़ी अधिक है। सत्ता की इस मात्रा को भी यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के नाम पर स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार प्रायः पूरे अफ्रीका में ही सरकार के नियन्त्रण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बीच बहुत असंतुलन होते हुए भी कोई इसका विरोध नहीं करता और न ही किसी को इससे असन्तोष होता है।

(6) राष्ट्रवाद की भावना ने अफ्रीका के देशों में एकरा का सूत्रपात किया और इसी एकरा के आधार पर वे विदेशी शक्तियों से अपने आपको मुक्त करा सके हैं। महाद्वीप के अधिकांश भाग पर राष्ट्रवाद का भारी प्रभाव है। हेच (Hatch) के शब्दों में स्वतन्त्रता एकरा की माँग करती है और राष्ट्रीयता की तेज मानसिक जगमग ने गारे देश को साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एकीकृत करने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। शिक्षा, सम्पत्ता एवं विज्ञान में पिछड़े होने के कारण यहाँ के देशों में राष्ट्रवाद उतना प्रभावशाली नहीं है जितना यह एशिया महाद्वीप में रहा है। यद्यपि राष्ट्रवाद के उदय को रोका नहीं जा सकता, तो भी अफ्रीका के बड़े क्षेत्र अभी तक राष्ट्रवाद के प्रभावशाली व्यवहार के लिए तैयार नहीं हैं अर्थात् यहाँ पर स्वशासन की स्थापना के अनुकूल वातावरण अभी तक नहीं बना है।

(7) अफ्रीका के देशों में नूतन जीवन के प्रति, स्वशासन के प्रति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रति, पारस्परिक सहयोग के प्रति तथा जातीय एकरा के प्रति प्रवृत्ति की भावनाएँ विद्यमान हैं। अफ्रीका अपने इसी रूप में अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में प्राया है। अब यह स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों का, घटनाओं का तथा मनमुटावों का प्रभाव इस महाद्वीप के देशों पर भी पड़े किन्तु वे देश प्राथमिक रूप में घातमनिर्भर नहीं हैं, इसीलिए किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर अपना स्वतन्त्र विचार नहीं रख सकते। अफ्रीका का प्राथमिक जीवन अब भी बहुत कुछ शेष सगर पर निर्भर करता है। इस प्राथमिक परनिर्भरता की प्रवृत्ति में जब ये देश उपनिवेशवाद में स्वतन्त्रता की स्थिति में आए, तो अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। नए राज्यों का निर्माण उन

प्रदेशों में से किया गया है जिनका यूरोपीय शक्तियों ने विभाजन कर रखा था। ये राज्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाते।

(8) प्रायः पूरे अफ्रीका-महाद्वीप में अफ्रीकीयन की भावना का प्रभाव है। सभी अफ्रीकी यह निर्णय कर चुके हैं कि सम्पूर्ण अफ्रीका पर भविष्य में केवल अफ्रीकियों का ही राज्य रहेगा। इस दृष्टिकोण के कारण अफ्रीका में विभिन्न सभ्यता तथा उपसभ्य बनाने के प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार किया जाता रहा है। इस प्रकार के सभ्य-निर्माण के मार्ग में बाधा, संचार-साधन तथा आर्थिक विकास जैसी कुछ बाधाएँ हैं जिनको दूर करने के बाद यहाँ के लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों में भी विकास होगा।

(9) अफ्रीका-महाद्वीप शीतयुद्ध के प्रसार को रोकने के लिए प्रयत्नशील है और इसी उद्देश्य से इसने अन्तर्राष्ट्रीय समाज में प्रवेश किया है। यद्यपि अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनेक कार्यों की ध्यालोचना करते हैं, तो भी यह उनके लिए एक आशा का प्रतीक है जो उनके आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में सहायक बनकर उन्हें विश्व-राजनीति को प्रभावित करने योग्य बना सकता है तथा पूर्व और पश्चिम के भगड़े से दूर रख सकता है। अफ्रीकी देश यह चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ साम्यवादी अथवा पूंजीवादी शक्तियों के हाथ की कठपुतली न रहकर पूर्व, पश्चिम और तटस्थ पक्ष का समान प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बन जाए। उनके मतानुसार यह संस्था उपनिवेशवाद, नवीन उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के नए तरीकों से झड़ती है। वे चाहते हैं कि यह उनके अपने आर्थिक विकास में सहायता करे, उनकी राजनीतिक परेशानियों में सहायक बने तथा यही एकमात्र अभिकरण है जो विश्व-युद्ध को रोकने की सामर्थ्य रखता है।

अफ्रीका में साम्यवाद (Communism in Africa)

साम्यवाद की प्रवृत्तियों का प्रभाव अफ्रीका-महाद्वीप पर एशिया महाद्वीप की अपेक्षा कम है। अफ्रीका की राजनीति में यह एक प्रकार का विरोधाभास सा दिखाई देता है। इस महाद्वीप में साम्यवाद के लिए प्रायः सभी आवश्यक परिस्थितियाँ उपस्थित हैं जिनके कारण इस विचारधारा का निर्वाह प्रचार एवं प्रसार किया जा सकता है। यहाँ के लोग आर्थिक शोषण तथा साम्राज्यवादी दमन एवं आतंकी के कटु अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, इनके प्रति यहाँ पर प्रबल विरोध की भावना विद्यमान होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पश्चिमी ढंग का प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्रता पर अधिक जोर देता है और समानता के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा कर सकता है, इस महाद्वीप के लोगों की आकांक्षों और महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाता। वे तो शीघ्र ही बीमारी से छुटकारा पाकर यथेष्ट भोजन की प्राप्ति में रुचि रखते हैं; अन्य अमूर्त आदर्शों में उनकी कोई रुचि नहीं है। साम्यवाद के पास इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन मौजूद हैं तथा उनके द्वारा दिए

गए आशवासनों के प्रति इस महाद्वीप के लोगों की रुचि बने रहना स्वाभाविक है। साथ ही साम्यवादी देशों द्वारा साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की सफलता तथा पुँजीपति वर्ग को समाप्त कर शोषण का अन्त, व्यक्तियों के बीच समानता की स्थापना और जातीय-भेदभाव की नीति की निन्दा आदि साम्यवादी नीतियों के कुछ उदाहरण हैं जो अफ्रीका निवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पर्याप्त से भी अधिक हैं इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सोवियत रूस और साम्यवादी चीन द्वारा इस महाद्वीप के अनेक देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया था। इस सहयोग की ये देश कभी भी नहीं भुला सकते। इन सबके होने के बाद अफ्रीका महाद्वीप पर साम्यवादी गुट की पूरी नज़र है तथा यहाँ से हटने हुए पश्चिमी प्रभाव के स्थान को वे स्वयं ग्रहण करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील हैं। अधिक असमानता के प्रति यहाँ के लोगों का दृष्टिकोण स्पष्ट है तथा इसके परिणामों से वे भली-भाँति परिचित हैं।

मूडान गणतन्त्र के राष्ट्रपति इब्राहिम अबूद (Ibrahim Abboud) ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में बोलते हुए कहा था कि "अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर स्थित असहयोग तथा अशान्ति का कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में असमानता है जो हमारे समय की एक विशेषता है तथा जो विश्व को अति धनवान और अति गरीब में विभाजित करती है। आर्थिक विकास के ये असन्तुलित स्तर ही असन्तोष तथा ईर्ष्या के बीज बोते हैं।" इन सब अनुकूल परिस्थितियों तथा वातावरण के रहने पर भी अफ्रीका में साम्यवाद का प्रभाव बहुत कम है। इसका कारण विश्व की वर्तमान स्थिति को माना जा सकता है। अफ्रीका-महाद्वीप को देगी से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का एक बड़ा लाभ यह प्राप्त हुआ कि जब वहाँ के देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर गाँव रखा तो इनके सामने स्पष्टतः दो विरोधी तथा प्रतिस्पर्द्धापूर्ण गुट थे। उनके बीच शीतयुद्ध एवं उसके भयानक परिणामों की कलाना करने में भी ये देश समर्थ थे। साथ ही दोनों से अलग रहने की गुटनिरपेक्षता की नीति का भारत के नेतृत्व में अनेक देशों ने पालन करना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसी स्थिति में सदियों बाद प्राप्त की गई अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के उद्देश्य से इन देशों ने भारत का अनुगमन करना ही उपयुक्त समझा। शीतयुद्ध की शान्त लपटों से यहाँ के नेता अपने प्रदेशों को बचाने के पक्ष में थे। इथियोपिया के कार्यवाहक राज्य मन्त्री कटेमा यिफ्रू (Katema Yifru) ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में कहा था कि "शीतयुद्ध का प्रसार एशिया और अफ्रीका के लिए विशेष खतरे का सूचक है तथा यह उनके शान्तिपूर्ण एवं बौद्धिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए चुनौतियों का सृजन करता है।" इसी प्रकार के विचार नादजीरिया के प्रधान मन्त्री सर अबूबकर बेलेवा (Sir Abubakar Belewa) ने कांगो की समस्या पर बोलते हुए प्रकट किए थे। उनका कहना था कि "अफ्रीका को मंडानिक संघर्ष की युद्धभूमि नहीं बनने देना चाहिए और कांगो की स्थिति पर अफ्रीकी राज्यों को राजनीतिक स्तर पर विचार करने देना चाहिए।"

इन समस्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों में साम्यवाद-विरोधी प्रवृत्तियाँ उपस्थित हैं तथा वे किसी भी बाद से अपने आपको बाँधना नहीं चाहते। कुछ विचारकों का मत है कि इस महाद्वीप के राष्ट्रीय आन्दोलनों पर साम्यवाद का अधिक प्रभाव नहीं था। अफ्रीका के कई देशों जैसे कंगो, अदिस अबाबा, श्रीटोरिया, मोनरोविया आदि में साम्यवादियों की कूटनीतिक चोकियाँ बनी हुई हैं तथा अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फाँसीसी पश्चिम अफ्रीका में स्थानीय साम्यवादी दलों का प्रभाव है। अफ्रीका के नेताओं में से बहुत कम ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। किन्तु यहाँ के विभिन्न देशों में साम्यवाद का प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से एजेंट भेजे जाते हैं तथा यह सम्भावना है कि यहाँ के कुछ देश साम्यवादी विचारधारा के प्रति झुक जाएँगे।

एशिया तथा अफ्रीका के जागरण में समानताएँ और अन्तर (Similarities and Dissimilarities in the Resurgence of Asia and Africa)

समानताएँ

1. एशिया और अफ्रीका दोनों ही में जागरण की सहर फैली हुई है। दोनों ही महाद्वीप साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरोधी हैं। दोनों ही क्षेत्र आज गुलामी से लगभग मुक्त हैं और जो कुछ भी साम्राज्यवादी अवशेष बचि हैं, उन्हें मिटा देने की कृत-संकल्प है।

2. दोनों ही महाद्वीपों का साम्राज्यवादी शक्तियों ने शताब्दियों तक शोषण किया, भ्रत. स्वभाषत. दोनों ही आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक रुढ़िवादिता से पीड़ित हैं। दोनों में व्यापक अशिक्षा है और समुचित राजनीतिक चेतना परिपक्व नहीं हो पाई है। महाशक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के अनेक राज्यों की राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक दुर्बलता का लाभ उठा कर अपने 'आर्थिक उपनिवेशवाद' और 'नव-उपनिवेशवाद' के प्रसार के लिए लालायित हैं। विश्व के बड़े देश, विशेषकर पश्चिमी शक्तियाँ, इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं कि एशिया और अफ्रीका में मधर्ष के ऐसे विस्फोटक केन्द्र बना दिए जाएँ कि यदि भविष्य में कोई महायुद्ध छिड़े तो वह इन दोनों महाद्वीपों की भूमि पर हो, यूरोप में नहीं।

3. दोनों ही महाद्वीपों में बहुसंख्यक राज्यों का नेतृत्व पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त नेताओं के हाथों में है, अतः उन राज्यों का विकास और राजनीतिक ढाँचा अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल न होकर बहुत कुछ पश्चिम-प्रेरित है। बहुत से देशों की जनता गरीबी और पिछड़ेपन की चक्की में पिस रही है, लेकिन पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित नेतृत्व सही स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है।

4. दोनों ही महाद्वीपों की शीतयुद्ध के परिणामों की भुगतना पड़ा है। दोनों को ही साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी 'पुनर्स्थापन प्रयत्नों' के प्रति सदैव सजग रहना पड़ता है।

5. दोनों ही महाद्वीप राष्ट्रवाद की लहर से झोत-झोत है तथा साथ ही साम्यवाद के प्रसार से आगकित है। नवोदित विशाल साम्यवादी चीन एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में, खासकर, निबल और छोटे देशों में, मार्क्सवाद के प्रसार के लिए बेचैन है। साम्यवाद-प्रेरित हिंसात्मक क्रान्तियों का विस्फोट जब तक होता रहता है पर धीरे-धीरे दोनों ही महाद्वीपों के राष्ट्र चीनी विस्तारवाद को भाँप गए हैं और उसके प्रभाव से बचे रहने को प्रयत्नशील हैं।

6 अपने आर्थिक और प्राविधिक विकास के लिए दोनों ही महाद्वीप विदेशी सहायता के लिए परमुखापेक्षी हैं। अतः सहायता देने वाली शक्तियों को सहायता प्राप्त देशों में अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के पर्याप्त अवसर मिलते रहते हैं।

अन्तर

1 एशिया का राष्ट्रवाद अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व है जबकि अफ्रीका का राष्ट्रवाद अभी बहुत-कुछ अपने शैशवकाल में है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि एशिया में भारत, चीन, जापान, बर्मा जैसे बड़े और विशालकाय देशों का अस्तित्व है जबकि अफ्रीका में छोटे-छोटे राष्ट्रों का आधिक्य है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी राष्ट्रों की तुलना में एशियायी राष्ट्रों में शिक्षा का अधिक प्रसार है।

2 अफ्रीका के राष्ट्रवाद को वहाँ की परिस्थितियों ने विशेष रूप से उग्र बना दिया है, जबकि एशियायी राष्ट्रवाद कतिपय अग्रवादों को छोड़कर सामान्यतः शान्तिपूर्ण तरीकों में विश्वास करता है।

3 अफ्रीका में उपनिवेशवादी शक्तियों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जब कि एशिया के बहुत से देशों में इन शक्तियों का अप्रत्यक्ष शासन था। अतः स्वभावतः दोनों महाद्वीपों के जागरण और चिन्तन की परिस्थितियाँ भिन्न रही जिनका प्रभाव आज भी स्पष्ट दिखाई देना है।

4 दोनों महाद्वीपों के जागरण में एक बड़ा अन्तर यह भी रहा है कि जहाँ एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने स्थायी रूप से बसने की नीति अपनाई वहीं अफ्रीका में यूरोपीय जातियाँ स्थायी रूप से बस गईं, अतः वहाँ अपेक्षाकृत अधिक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो गईं।

5 रंग-भेद और कबीलेवाद की समस्याएँ एशिया की अपेक्षा अफ्रीका में निरन्तर अधिक गम्भीर रही हैं। अब 'अफ्रीकीकरण' की नई लहर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और मानवीय पहलुओं को दूषित कर रही है।

6 अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अफ्रीकी नेता एशियायी नेताओं की तुलना में अधिक उग्र रहे हैं और उन्हें एशिया वालों की 'निष्प्रियता' पसन्द नहीं आई। इसमें अफ्रीकी-एशियायी एकता आन्दोलन को बड़ा नुकसान पहुँचा है।

7. एशिया महाद्वीप की तुलना में अफ्रीका महाद्वीप की राजनीतिक परम्पराएँ प्रारम्भ से ही बहुत अधिनायकवादी और सर्वमत्तावादी रही, अतः वहाँ के किसी भी देश में स्वस्थ सोवतन्त्रीय परम्पराओं का विकास नहीं हो सका।

इसके विपरीत एशिया के भारत आदि देशों में लोकतन्त्र ने इतनी प्रगति करली कि स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत तो विश्व में लोकतन्त्र का शक्तिशाली दुर्ग बन गया है।

8. एशिया की तुलना में अफ्रीका में साम्यवादी प्रभाव अभी तक विशेष रूप से उग्र नहीं हो पाया है, तथापि साम्यवादी देशों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध अफ्रीका-वासियों के स्वर्ण को नैतिक बल पहुँचाने में सक्रिय सहायता दी है और वे अब अफ्रीका के शम-प्रान्दोलनों के साथ गठजोड़ कर वहाँ साम्यवाद के प्रसार के लिए सचेष्ट हैं।

9. एशिया की तुलना में अफ्रीका के देश प्राथिक तथा औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं, यद्यपि प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से अफ्रीका संसार का एक अति सम्पन्न महाद्वीप है।

एशिया और अफ्रीका के जागरण के प्रतीक महत्त्वपूर्ण संगठन और सम्मेलन

द्वितीय युद्ध के बाद एशिया एकदम जाग उठा और जागरण के सन्देश से अफ्रीका महाद्वीप भी झकझोरना न रह सका। दोनों महाद्वीपों के विभिन्न देशों में सम्पर्क का प्रसार हुआ। द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में समय-समय पर एशिया और अफ्रीका के स्वाधीन और विश्व के तटस्थ राष्ट्रों ने अपने सम्मेलनों द्वारा एशिया और अफ्रीका के जागरण का सन्देश दिया, उपनिवेशवाद की जड़ें हिलाई और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर गम्भीर विचार-विमर्श कर अपना यह महत्त्व जता दिया कि यूरोपीय देश अब अफ्रीकियाई देशों की उपेक्षा नहीं कर सकते। यहाँ हम प्रमुख अफ्रीकियाई सम्मेलनों और मण्डलों पर एक बिहगम दृष्टि डालेंगे। गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलनों का आगे गुटनिरपेक्षता सम्बन्धी एक पृथक् अध्याय में वर्णन किया गया है।

प्रथम एशियायी सम्मेलन, 1947

श्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से इण्डियन कोसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (Indian Council of World Affairs) ने मार्च-अप्रैल, 1947 में एशियायी देशों के एक गैर-सरकारी सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सदस्यों ने एशियायी देशों की राजनीतिक स्वतन्त्रता, उनके आर्थिक विकास, रण-भेद, आदि विभिन्न समस्याओं पर विचार किया। एशियायी देशों का एक स्थायी संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि एशियायी देश आपस में मिलकर ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सम्मेलन ने विश्व को यह संकेत दे दिया कि एशिया अब जाग चुका है और अधिक समय तक उस पर साम्राज्यवादी शासन स्थापित नहीं रह सकता।

द्वितीय एशियाई सम्मेलन, 1949

भारत सरकार के आमन्त्रण पर देहली में 1949 में 20 से 30 जून तक एशियायी

देशों का द्वितीय सम्मेलन हुआ जिसका मूल उद्देश्य इण्डोनेशिया पर डच आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार करना था। सम्मेलन में डच-कार्यवाही की कठोर शब्दों में निन्दा की गई, डच-आक्रमण को असफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए और सुरक्षा-परिषद्, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड का सहयोग प्राप्त कर हालैंड के प्रति कठोर रुख अपनाने की नीति निर्धारित की गई।

बाँडुंग सम्मेलन, 1955

1955 में 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक इण्डोनेशिया के नगर बाँडुंग में एशिया और अफ्रीका के लगभग 29 राष्ट्रों के इस सम्मेलन पर 'एशिया का जागरण' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाश डाला जा चुका है। वास्तव में इस सम्मेलन द्वारा एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों के जीवन में एक नवीन आत्म-विश्वास और आशा का उदय हुआ तथा सम्पूर्ण विश्व में एशिया की एक नई आवाज गूँज उठी कि एशिया और अफ्रीका के वासी अब पराधीन नहीं रहेंगे, अपने हाथों अपने भविष्य का निर्णय करेंगे, स्वतन्त्रता तथा शान्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को उखाड़ फेंकेंगे। एशिया की राजनीति के दृष्टिकोण से बाँडुंग-सम्मेलन के दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले—

प्रथम इसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं के प्रति एशिया और अफ्रीका के एक समान दृष्टिकोण को जन्म दिया।

द्वितीय, समुक्त राष्ट्रसंघ में एक ऐसे एशियायी गुट की आधारशिला रखी जिसने आगे चलकर पूर्व और पश्चिम के संघर्ष में सन्तुलन पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

मोशी सम्मेलन, 1963

फरवरी, 1963 में मोशी (टंगानिया) में अफ्रीकियायी एकता सम्मेलन हुआ जिसमें—(1) ब्रिटेन से अपील की गई कि वह वासुनोलैण्ड, बेनुमानालैण्ड तथा स्वाजीलैण्ड को अविलम्ब बिना शर्त स्वतन्त्रता प्रदान करदे, (2) सभी राष्ट्रों से अपील की गई कि उपनिवेशवादी शक्तियों के दमन से पीड़ित लोगों को राजनीतिक शरण दी जाए; (3) इजरायल की इस बात के लिए निन्दा की गई कि वह एक नया उपनिवेशवादी झड़्डा बनता जा रहा है; (4) चीन के पारमोसा को मुक्त करने के अधिकार का समर्थन किया गया; (5) सभी राष्ट्रों से अपील की गई कि पुर्तगाल के विरुद्ध आर्थिक एवं कूटनीतिक बहिष्कार लागू कराएँ तथा अगोला और मोजाम्बिक के मुक्ति-ग्रामोन्नों को सहायता दें; (6) उत्तरी रोडेशिया को लोकतान्त्रिक संविधान प्रदान करने और संघ को भंग करने की माँग की गई तथा राष्ट्रों से अपील की गई कि वे दक्षिणी रोडेशिया के लोगों को उनके मुक्ति-संग्राम में सहयोग दें; (7) अमेरिका से विपतनाम में अपनी आक्रामक कार्यवाहियाँ बन्द करने की अपील की गई; (8) ब्रिटेन को सुभाष दिया गया कि वह सन् 1963 के अन्त तक जर्जीवार को स्वतन्त्र करदे; (9) एक प्रस्ताव में कहा गया कि समुक्त राष्ट्रसंघ

अमेरिकी साम्राज्यवाद का साधन न बने तथा सभी राष्ट्रों से अशोक की गई कि वे इस विश्व-संस्था के पुनर्गठन पर बल दें ताकि वह एशिया और अफ्रीका के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सके।

अदिस अबाबा सम्मेलन, 1963

मई, 1963 में एक अफ्रीकी सम्मेलन हुआ जिसमें 32 स्वतन्त्र राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। यह सम्मेलन इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में हुआ। इसने संयुक्त अफ्रीका की स्थापना के विषय में विचार किया गया और अफ्रीकी राष्ट्रों के एक स्थायी सचिवालय की स्थापना तथा सभी राज्यों के परराष्ट्र मंत्रियों की एक मन्त्रि-परिषद् की स्थापना का सुझाव दिया गया। इन निश्चयों के अनुसार कार्य भी हुआ। सचिवालय का नाम अफ्रीकी-एकता-संगठन रखा गया। सम्मेलन ने अफ्रीकी राज्यों के भगड़ों को सुलभाने के लिए एक प्रायोग की स्थापना भी की। सम्मेलन द्वारा यह निश्चय किया गया कि अफ्रीका के पराधीन देशों को औपनिवेशिक दासता से तथा दक्षिण-अफ्रीका की अश्वेन जनता को रंगभेद-नीति के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए एक मुक्ति-सेना का गठन किया जाए और मुक्ति-कोष की भी स्थापना की जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि दक्षिणी अफ्रीका और पुर्तगाल के विरुद्ध राजनीतिक व आर्थिक बहिष्कार की नीति अपनाई जाए। संयुक्त राष्ट्रसंघ से मांग की गई कि वह सुरक्षा-परिषद् तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद् में अफ्रीकी राष्ट्रों को आनुपातिक स्थिति प्रदान करे। ब्रिटेन से कहा गया कि वह दक्षिणी रोडेजिया को तब तक स्वतन्त्रता प्रदान न करे जब तक वहाँ अफ्रीकी जनता को शेरों से समान अधिकार प्राप्त न हो जाएँ। अदिस अबाबा सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें अफ्रीकी एकता का एक घोषणापत्र स्वीकार किया गया जिसमें समूचे अफ्रीकी महाद्वीप को दासता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की गई। इस कार्य के लिए नौ अफ्रीकी देशों टांगानिका, मलजीरिया, इथियोपिया, संयुक्त अरब गणराज्य, उगाण्डा, कांगो, गिनी, सेनेगल नेया, नाइजीरिया को मिलाकर एक स्वाधीनता-समिति (Liberation Committee) बनाई गई। इनका प्रधान कार्यालय दारेस्तलाम में रखा गया।

अफ्रेशियाई एकता सम्मेलन, 1972

जनवरी, 1972 में काहिरा में अफ्रेशियाई एकता सम्मेलन हुआ जिसमें 59 देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों ने भाग लिया। सम्मेलन ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल के विरोधी खड़े के बावजूद भारत और बंगलादेश के न्यायपूर्ण हक का समर्थन किया। केवल लीबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। मुस्लिम राष्ट्रों ने नवोदित बंगलादेश का पक्ष लिया और भारतीय उपमहाद्वीप की वास्तविकता को मान्यता दी। बंगलादेश के प्रतिनिधि-मण्डल को आमन्त्रित किया जाना ही इस बात का प्रमाण था कि अफ्रेशियाई देशों ने उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है, चाहे उस समय तक उसे औपचारिक रूप से मान्यता न दी गई हो। बंगलादेश के अलावा सम्मेलन में मॉरिशस, हिन्द-चीन तथा अफ्रीकी मुक्ति-युद्धों पर

भी बुनकर विचार-विमर्श हुआ और अफ्रीकियायी देशों का साम्बा बाजार बनाने की भी प्रेरणकश की गई ।

अफ्रीकी एकता संगठन

25 मई, 1962 को 30 अफ्रीकी देशों ने अदिस अबाबा सम्मेलन में 'अफ्रीकी एकता संगठन' की स्थापना के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए । वही इस संगठन का मुख्यालय भी है । अफ्रीकी देशों के बीच एकता और सहयोग बढ़ाना, उपनिवेशवाद को समाप्त करना तथा सदस्य देशों की स्वाधीनता की रक्षा के लिए कार्य करना संगठन का मुख्य उद्देश्य है । संगठन की सरकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी स्वीकार की गई है । इसके अलावा अफ्रीका की सभी देशी भाषाओं की काम-काज की भाषा का स्तर प्राप्त हुआ । संगठन के महत्वपूर्ण निर्णय समय-समय पर सदस्य-देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक तथा शिखर-सम्मेलनों के माध्यम से लिए जाते हैं । अफ्रीकी देशों के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करना ही इसका मुख्य काम रहा है ।

स्थापना के बाद से ही अफ्रीकी एकता संगठन के सम्मेलन विभिन्न अवसरों पर होते रहे हैं । पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीकी एकता संगठन की जो गतिविधियाँ रही हैं, उनका सारांश इस प्रकार है—

विदेश मन्त्री सम्मेलन, जून 1976 (पोर्टो न्यू)—अफ्रीकी एकता संगठन का छ दिवसीय 27वाँ सम्मेलन 24 जून, 1976 को पोर्टो न्यू (मारिशस) में आरम्भ हुआ । अफ्रीकी एकता संगठन के 48 सदस्यों के विदेश मंत्रियों ने दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया और फ्रांस की भर्त्सना के साथ अपनी मन्त्रणा आरम्भ की । सम्मेलन के अध्यक्ष, मारिशस के प्रधान मन्त्री सर शिवसागर रामगुनाम ने अपने उद्घाटन भाषण में यह आह्वान किया कि सभी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अफ्रीका और उसके मददगारों की एक स्वर में निन्दा करनी चाहिए । दक्षिण-अफ्रीका के बहिष्कार और रणभेद मिटाने के लिए अफ्रीकी-एकता-संगठन का सकल्प और उसके लिए उनकी चार सूची योजना यह थी—

1. आर्थिक और अन्य प्रकार के बहिष्कारों द्वारा दक्षिण-अफ्रीका को भ्रष्ट-धलन करना ।

2. अफ्रीकी-एकता-संगठन द्वारा दक्षिण-अफ्रीका के विरुद्ध मुनियोजित राजनीतिक तथा कूटनीतिक कार्यवाही करना ।

3. दक्षिणी-अफ्रीका, नामीबिया और जिवाब्वे (रोडेजिया) के मुक्ति प्रान्तों को वास्तविक अधिकारों से सम्पन्न करना ।

4. दक्षिण-अफ्रीका की समस्या में निपटने के लिए ठोस उपाय सुझाने हेतु एक समिति की स्थापना करना ।

पोर्टो न्यू सम्मेलन का यह प्रस्ताव भी अपने में काफी महत्वपूर्ण था जिसके द्वारा अरब देशों में यह अनुरोध किया गया कि वे दक्षिण-अफ्रीका को तेल देने पर नये प्रतिबन्धों को धीरे-धीरे लागू करें ।

शिखर सम्मेलन, जुलाई 1976 (मारिशस)—जुलाई, 1976 के प्रथम सप्ताह में अफ्रीकी-एकता-संगठन में सम्मिलित 48 देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन मारिशस में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में घोषणा की गई कि अफ्रीकी महाद्वीप में स्वाधीनता संघर्ष को तत्काल सहायता देने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। फ्रांस और पश्चिम जर्मनी द्वारा दक्षिण अफ्रीका सरकार को परमाणु भिद्री उपलब्ध कराने की सभी अफ्रीकी शासनाध्यक्षों के द्वारा निन्दा की गई। शिखर सम्मेलन में इजरायली आक्रामक रवैये की निन्दा करते हुए इस बात पर सहमति व्यक्त की कि एकता संगठन के सदस्य देशों को इजरायल को अलग-थलग करने की कार्रवाहियाँ तेज कर देनी चाहिए।

अफ्रीकी एकता संगठन के इस शिखर सम्मेलन के निर्णय स्पष्ट तौर पर विदेश-मन्त्री सम्मेलन के प्रस्तावों से प्रभावित थे।

अखिल-अफ्रीकावाद (Pan-Africanism)

अखिल-अफ्रीकी आतृत्व आन्दोलन अथवा अखिल-अफ्रीकावाद (Pan-Africanism) इस महाद्वीप के एकीकरण का एक बहुत प्राचीन आन्दोलन है। इस आन्दोलन का ध्येय 'संयुक्तराज्य अफ्रीका' की स्थापना है। सबसे पहले 1900 में लन्दन में पान-अफ्रीकी सम्मेलन हुआ और तब से समय-समय पर ये सम्मेलन होते रहे हैं जिनमें अफ्रीका को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने सम्बन्धी निर्णय लिए गए हैं। पाना के स्वतन्त्र होने पर अफ्रीका में जब यह सम्मेलन हुआ (इसके पहले यह आन्दोलन अफ्रीका के बाहर ही था) तो इसके मुख्य उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया गया। ये उद्देश्य संकेत रूप में इस प्रकार हैं—

1. अफ्रीका के सभी देशों का एक संघ बनाया जाए। क्षेत्रीय आधार पर भी संघ बनाए जा सकते हैं, जैसे—उत्तर-अफ्रीका-संघ, पश्चिमी-अफ्रीका-संघ, केन्द्रीय-अफ्रीका-संघ, दक्षिण-अफ्रीका-संघ आदि।
2. उपनिवेशवाद जातिवाद और रंगभेदवाद का विरोध किया जाए।
3. अहिंसात्मक साधनों और तटस्थ नीति को प्रोत्साहन दिया जाए।

पहले पान-अफ्रीकी सम्मेलनों में अफ्रीकी देशों की स्वतन्त्रता पर अधिक बल दिया जाता था। अब अफ्रीका महाद्वीप लगभग स्वतन्त्र हो चुका है, अतः सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 'अफ्रीकी व्यक्तित्व' की कल्पना को साकार बनाना है किन्तु इस लक्ष्य की पूर्ति कोई आसान काम नहीं है क्योंकि अफ्रीका के देश आपसी फूट के शिकार हैं। इस महाद्वीप में विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, परम्पराओं और धार्मिक विचारों का पोषण होता है। अफ्रीका के देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, शिक्षा की दृष्टि से अफ्रीका के अधिकांश देश काफी पिछड़े हुए हैं एवं अधिकांश अफ्रीकी राज्यों के नेता उग्र तथा अस्थिर प्रकृति के हैं।

अरब लीग

अरब लीग अरबों की राष्ट्रीय जागृति की प्रतीक है। इसकी स्थापना मिस्र, जोर्डन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, ईराक और यमन के बीच 1945 में एक

समझौते के फलस्वरूप हुई। बाद में लीबिया, सूडान, मोरक्को आदि अनेक अरब देश इसमें सम्मिलित हो गए। लीग का मुख्य उद्देश्य अरब-देशों में एकता और सहयोग का प्रसार करना है, अरबों की आपसी फूट के कारण अभी तक इस दिशा में उत्साहजनक प्रगति नहीं हो सकी है।

विश्व-राजनीति में तेल उत्पादक अरब देशों का महत्त्व बढ़ने के साथ-साथ उसके एकमात्र राजनीतिक संगठन के रूप में अरब लीग का महत्त्व भी काफी बढ़ गया है। अक्टूबर, 1974 में अरब लीग के तत्वावधान में अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की रवात में बैठक हुई जिसमें फिलिस्तीनी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को फिलिस्तीनियों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई।

कम्पाला सम्मेलन, जुलाई-अगस्त, 1975

अफ्रीका-एकता-संगठन का 12वाँ सम्मेलन 28 जुलाई से 1 अगस्त, 1975 तक उगाण्डा की राजधानी कम्पाला में हुआ। यह सम्मेलन अफ्रीकी एकता के बीच विद्यमान दंगरों को व्यक्त करने वाला सिद्ध हुआ। संगठन के 45 सदस्य देशों में से उगाण्डा सहित 20 देशों ने ही भाग लिया। अफ्रीकी एकता के दृढ़ स्तम्भ तांज़ानिया के राष्ट्रपति जुलियस न्येरेरे, जाम्बिया के केनेथ काउण्डा, नवस्वाधीन मोजाम्बिक के राष्ट्रपति समोरा माइकेल और बोत्स्वाना के प्रधान मंत्री सर सेरेत्से खामा जैसे महत्त्वपूर्ण नेता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। काफी विवाद के बाद उगाण्डा के राष्ट्रपति ईशोममीन सम्मेलन के अध्यक्ष बने।

कम्पाला सम्मेलन पारस्परिक फूट और आशंका का शिकार बना रहा। इजरायल के विरोध के सम्बन्ध में भी संगठन में एकता न हो पाई। अन्त में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि इजरायल पर दबाव बढ़ाना चाहिए और यदि वह अरब-भूमि खाली न करे तो अन्ततः उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। फिलिस्तीनी मुक्ति-मोर्चे को बड़ा क्षोभ हुआ और उसके नेताओं ने मिस्र पर आरोप लगाया कि इजरायल की संयुक्तराष्ट्र की सदस्यता का मिस्र ने 'असम्मानजनक बचाव' किया है और 'मुट्ठी भर सिनाय' के बदले इजरायल का पक्ष लिया है। सम्मेलन में दक्षिणी-अफ्रीका और रोडेशिया के प्रश्न पर भी विचार किया गया और कहा गया कि जब तक वहाँ बहुमत का शासन स्थापित न हो जाए, तब तक अफ्रीकी एकता संगठन को वहाँ के राष्ट्रवादियों के स्वाधीनता सघर्ष का समर्थन करते रहना चाहिए। अंगोला में गृहयुद्ध में उलझे हुए विभिन्न पक्षों से तुरन्त युद्ध-विराम करने के लिए कहा गया। सम्मेलन में संगठन सम्बन्धी कई प्रश्नों पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

अदिस-अबाबा का विशेष सम्मेलन

(जनवरी 1976) और अंगोला में युद्ध

11 नवम्बर, 1975 को पुर्तगाली साम्राज्यवाद से मुक्ति पाते ही अंगोला में पहले से ही प्रारम्भ गृहयुद्ध में तीव्रता आ गयी और कुछ ही घंटों के भीतर तीनो प्रमुख दलों—'अंगोला जनमुक्ति फ्रान्कोलन' (एम. पी. एन. ए.) अंगोला, राष्ट्रीय

मुक्ति मोर्चा (एफ. एन. एल. ए.) और अंगोला पूर्व स्वाधीनता सघ (यूनिटा) ने अंगोला के विभिन्न भागों में अपनी स्वतन्त्र सरकारों की घोषणा कर दी। महाप्रतियोगी अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए उनकी पीठ पर थी। अनेक अफ्रीकी देशों, पूर्वी यूरोपीय देशों तथा सोवियत सघ के समर्थन के फलस्वरूप अंगोला भी राजधानी उगाण्डा स्थित अंगोला जनमुक्ति आन्दोलन की सरकार का पलड़ा भारी हो गया। राजधानी में अगस्टीनो नेतों की सरकार को उन सभी अफ्रीकी देशों में मान्यता दे दी गई जो कभी पुर्तगाली शासन में थे। अमेरिका और चीन अंगोला राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सरकार को समर्थन दे रहे थे।

गृहयुद्ध को रोकने तथा अंगोला में पुनः एकता स्थापित करने के लिए अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा 10 जनवरी, 1976 को इथियोपिया की राजधानी अदिम अबाबा में एक विशेष शिखर सम्मेलन बुलाया गया, किन्तु उसमें अन्तिम रूप से समस्या का ऐसा कोई समाधान नहीं ढूँढा जा सका जो सभी पक्षों को मान्य हो। बैठक के दो प्रमुख उद्देश्य थे—गृहयुद्ध और विदेशी हस्तक्षेप से अंगोला की रक्षा, एवं अंगोला में विभिन्न मुक्ति आन्दोलनों द्वारा स्थापित सरकारों में से किसी एक सरकार को मान्यता। 46 अफ्रीकी राष्ट्रों में से 22 देश अगस्टीनो नेता की सरकार को मान्यता दे चुके थे जबकि 22 अन्य देशों का मत था कि मुख्य युद्ध-विराम करके विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त तीनों दलों की एक राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापित की जाए और शेष दो देशों (इथियोपिया तथा उगाण्डा) लगभग तटस्थ थे। बुनियादी मतभेदों के कारण सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और समस्या पर छ. महीने बाद पुनः विचार करने का निश्चय किया गया। अगस्टीनो नेतों के नेतृत्व में अंगोला जनमुक्ति आन्दोलन की सरकार की स्थिति निरन्तर सुदृढ़ होती रही और फरवरी, 1976 में उगाण्डा में जो अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसका उद्घाटन राष्ट्रपति अगस्टीनो नेतों ने ही किया। उन्होंने घोषणा की कि हमारा सघर्ष तब तक चलना रहेगा जब तक अंगोला पूर्ण स्वाधीन और एक नहीं हो जाता।

एशियान शिखर सम्मेलन (फरवरी 1976)

इण्डोनेशिया के बाली द्वीप में 23-24 फरवरी, 1976 को दक्षिण पूर्व-एशियाई राष्ट्रों के सघ (एशियान) का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। इसका उद्घाटन इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुहर्तो ने किया। पाँच देशों—इण्डोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपीन में, यद्यपि कई तरह के विवाद विद्यमान थे, लेकिन बातचीत मैत्री और सहयोगपूर्ण वातावरण में हुई। एशियान का गठन नौ साल पहले हुआ था। इस नौ साल के समय में इन देशों के सम्मेलन तो होने रहे, लेकिन कभी सहमति का ध्वजारोपण नहीं हुआ। राष्ट्रपति सुहर्तो ने इस बात पर जोर दिया कि हमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एकता को मजबूत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि हमारा उद्देश्य सैनिक युद्ध की स्थापना नहीं है तथापि हम लोग यह जरूर चाहते हैं कि हमारी क्षेत्रीय असंख्यता बनी रहे ताकि हम लोग किसी भी तरह के आर्थिक खतरे का मुकाबला शान्ति और दृढ़तापूर्वक कर

सकें। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि एक संयुक्त सन्धि थी जिसका उद्देश्य परस्पर सहयोग और मैत्री को बढ़ावा देना था। अधिक क्षेत्रों में दो कार्यक्रम स्वीकार किए गए—पेट्रो रसायन, इस्पात, खड़, पोटाश और टिन प्लेट में बड़े पैमाने पर संयुक्त औद्योगिक सयन्त्रों की स्थापना और व्यापार में एशियान देशों को प्राथमिकता देना। यह कहा गया कि एशियान देशों को एक-दूसरे की स्वाधीनता, प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करना चाहिए।

एशियान सम्मेलन, अगस्त 1977

अगस्त 1977 में क्वालालम्पुर में एशियान देशों का शिखर सम्मेलन हिन्दचीन देशों के साथ और अधिक सद्भाव तथा सहयोग बढ़ाने की मंजूरि के साथ समाप्त हुआ। सम्मेलन में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की हालाँकि कटु आलोचना की गयी, तथापि अन्ततः एशियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिकाधिक सहयोग समूचे एशियाई क्षेत्रों के हित में है। कहा गया कि पारस्परिक हितों की रक्षा तथा शान्ति के लिए एशियान क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बहुत आवश्यक है। सम्मेलन में भाग लेने वाले पाँच देशों ने अपना संकल्प दोहराया कि हम समूचे दक्षिण-पूर्वी एशिया को शान्ति, स्वतन्त्रता और स्थिरता का एक क्षेत्र बनायेंगे। अधिक सहयोग के बारे में सम्मेलन किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका। सम्मेलन में इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी कि विकासशील देशों में संरक्षण प्राप्त करने की भावना बढ़ रही है, जो इन देशों के लोगों के लिए हितकर नहीं है। विकासशील देशों से अनुरोध किया गया कि वे संरक्षण प्राप्त करने की भावना का जल्दी से जल्दी त्याग करें और आत्मनिर्भरता के अपने प्रयत्न जारी रखें।

अफ्रीकी एकता संगठन का 15वाँ अधिवेशन, जुलाई 1978

जुलाई 1978 में खारतूम में अफ्रीकी एकता संगठन का 15वाँ अधिवेशन हुआ जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि सदस्य राष्ट्रों में किसी भी समस्या पर मतभेद नहीं था तथापि इस बारे में सभी सदस्य राष्ट्र सहमत प्रतीत हुए कि अफ्रीकी में विदेशी हस्तक्षेप को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, अन्यथा अफ्रीका शान्तियों का युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। इस सहमति के बावजूद यह विचित्र बात थी कि अधिवेशन में सदस्य देशों को यह छूट दे दी गयी कि वे अपनी इच्छानुसार विदेशों से सैनिक तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अधिवेशन का यह निर्णय अप्रत्यक्ष रूप में विदेशी हस्तक्षेप के मार्ग को प्रशस्त करने वाला ही कहा जाएगा।

सम्मेलन में मतभेद सुनकर सामने आए। अफ्रीकी देशों में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति का प्रश्न रहा हो अथवा रोडेशिया की मुक्ति का या कोमोरो द्वीप समूह की गणतन्त्र की सदस्यता का, सभी प्रश्नों पर संगठन को अलग-अलग घंटों में बंटा पाया गया। संगठन के सदस्य साम्यवाद समर्थक देशों को यदि जेयरे में जमीनी सेना की उपस्थिति पर आपत्ति हुई तो जेयरे ने अंगोला आदि में क्यूबाई और रंगी सैनिकों की उपस्थिति पर अपनी-अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कुछ सदस्य देशों

ने रोडेज़िया में स्मिथ-सिथोले मुजोरेवा की संक्रान्तिकालीन सरकार का समर्थन किया तो दूसरों ने एन्जोमा मुगाबे के राष्ट्रवादी मोर्चे का साथ दिया। ऐसे ही मतभेद के कारण कोमोरो के प्रतिनिधि मण्डल को बरेंग स्वदेश लौटना पड़ा क्योंकि बहुमत ऐसी सरकार को प्रतिनिधित्व देने के विरुद्ध था जिसकी स्थापना में भाड़े के गोरे सैनिकों का हाथ रहा हो।

इन सब आपसी मतभेदों का परिणाम यह हुआ कि अधिवेशन बिना किसी ठोस उपलब्धि के समाप्त हो गया। यह प्रवश्य है कि गुट-निरपेक्षता के बारे में सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। सभी का यह मन था कि इससे अफ्रीका की स्वाधीनता, स्थिरता और सम्पन्नता को बनाए रखने के अफ्रीकी एकता सगठन के प्रयासों को सीधा समर्थन मिलेगा। अफ्रीका में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया गया। यह माना कि यदि यह हस्तक्षेप बना रहा तो अफ्रीका बड़ी शक्तियों का युद्धक्षेत्र बन जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति और रंगभेद की नीति के विरुद्ध

अन्तर्राष्ट्रीय दिल्ली सम्मेलन (अक्टूबर 1978)

दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति और रंगभेद की नीति के विरुद्ध नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन (28 सितम्बर से 2 अक्टूबर 1978) एक महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा। अपनी किस्म के इस दिवस पर इतने बड़े पहले सम्मेलन में 80 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जिस तरह की एकता और नयी शक्ति में बढ़ती हुए साम्राज्यवाद से उत्पन्न खतरे के प्रति आवाज बुलन्द की गयी, उससे निःसन्देह आन्दोलनों के समर्थकों को बल मिला। एक से अधिक बार जब यह कहा गया कि अब अधिक समय तक काले-बोरो के अधीन नहीं रहेंगे, उनका दमनचक्र अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा तो इस तरह की भावनाओं का सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। वक्ताओं ने चीन और बियतनाम तथा चीन और सोवियत संघ के सम्बन्धों पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए चीन की विस्तारवादी नीतियों की आलोचना की। चीन के इस प्रलम्ब में यदि किसी देश का उसे समर्थन मिला तो वह था रोमानिया। इस सम्मेलन में हर वक्ता ने बढ़ते हुए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खतरे के प्रति आगाह करते हुए कहा कि बहुराष्ट्रीय नियमों का फंलाव नई तरह के साम्राज्यवाद का प्रतीक है।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री सजीव रेड्डी ने कहा कि शान्ति, स्वतन्त्रता और मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करना आज सारी मानवता के लिए आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे की बहुत जरूरत है जो तभी सम्भव है जब अस्त्रों की दौड़ को समाप्त किया जाए। राष्ट्रपति ने रंगभेद और नस्लवाद की भावना को मानवता के विरुद्ध अपराध तथा सार्वभौमिक शान्ति के लिए खतरा बताया। प्रमुख नेताओं ने यह मत व्यक्त किया कि आज हर व्यक्ति साम्राज्यवाद और नव-उपनिवेशवाद के खिलाफ मोर्चे लगा है। नामीबिया के बारे में आत्म-निर्णय की माँग की गयी।

सम्मेलन में विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं— संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए एक सन्देश में कहा गया है कि जिस प्रकार साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभाव बढ रहा है उससे एक नये प्रकार का शीतयुद्ध जिसे 'नवशीतयुद्ध' का नाम दिया गया है, विश्वव्यापी हो रहा है। भूँ5 और बेनुनियादी धारणाओं पर आधारित प्रचारसाधन जोर पकड़ते जा रहे हैं। ये साम्राज्यवादी देश बड़े पैमाने पर अस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं जो मानव-जाति के लिए खतरा साबित हो सकते हैं नाटो देश इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इस समय परमाणु प्रदाय और सैनिकीकरण का जो भूत दक्षिण अफ्रीका की अल्पमत सरकार पर बड़ा हुमा है उससे अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय मूल्यों का हनन होगा। यदि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, इजरायल, ईरान और जापान इन अल्पमत सरकारों, दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया का समर्थन न करें तो ये कभी भी चमरा सकती हैं। एक अन्य प्रस्ताव में अंगोला, बोत्स्वाना, मोजाम्बिक, तांजानिया और जाम्बिया के प्रति जिम्बाब्वे और नामीबिया के मुक्ति आन्दोलन का समर्थन करने के लिए आधार व्यक्त किया गया।

इस्लामी सम्मेलन (फरवरी 1980)

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में इस्लामी देशों से फरवरी 1980 के विदेश-मन्त्री सम्मेलन में ग्राम तीर पर दो बातों के बारे में पूर्ण सहमति पायी गयी। एक तो इस्लामी देशों की कोई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरे पूर्व यूरोप हो अथवा पश्चिम, सभी से मुसलमानों के हितों की रक्षा का कोई सामूहिक प्रबन्ध होना चाहिए। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के फलस्वरूप इस्लामी देशों के विदेश मन्त्रियों का यह सम्मेलन बहुत जल्दी बुलाया गया था।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जनरल जिया उल हक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण इस्लामी दुनिया के लिए जर्बदस्त खतरा है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यह पहला अवसर है कि जब किसी महाशक्ति ने प्रभुमत्तामय एक स्वतन्त्र मुस्लिम देश पर हमला बोल दिया है। यदि छोटे देशों के विरुद्ध बड़े देशों की इसी प्रकार की जोर जर्बदस्ती को बक्त रहते नहीं रोका गया तो किसी देश का स्वतन्त्र रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इन हालात का मुकाबला करने के लिए इस्लामी देशों को एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की बात सोचनी चाहिए। भाषण के दौरान जनरल जिया ने इस्लामी देशों की सम्भावित भावों नीतियों का स्पष्ट संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि सोवियत तब तक इस सम्मेलन की यह घोषणा पट्टेच जानी चाहिए कि अफगानिस्तान ने सोवियत सैनिकों की मौजूदगी को हम बहुत गम्भीर मामला समझ रहे हैं और इस प्रकार के सैनिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने काफी लम्बे भाषण के बाद एक के बाद एक इस्लामी देशों के एक विदेशमन्त्री मंच पर आते रहे और कठे शब्दों में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप की निन्दा करते रहे।

सम्मेलन में शुरू के दिन जिया उल हक ने कश्मीर का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि फिलीस्तीनियों और कश्मीरियों को उनके अधिकार दिलाने का

मसला भी पाकिस्तान के सामने है। इस उल्लेख पर इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूत श्री बाजपेयी सम्मेलन से उठ कर चले गए। कुल मिलाकर 43 इस्लामी देशों के विदेशमन्त्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस्लामाबाद स्थित कुछ देशों के राजदूत प्रेक्षक के रूप में आमन्त्रित थे। सोवियत संघ और वारसाउ सन्धि के अन्य देशों ने सम्मेलन का बहिष्कार किया।

तीन दिन के इस सम्मेलन में विभिन्न इस्लामी देश के विदेश मन्त्रियों ने इस्लामी देशों की एकता के बारे में अपने सुझाव रखे, लेकिन सऊदी अरब के विदेश मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कुछ बातें सामने रखी। सऊदी अरब ने एक दस मुत्री कार्यक्रम भी पेश किया जिसके आधार पर सम्मेलन ने अपना प्रस्ताव तैयार किया था। प्रस्ताव के मसविदे को खाड़ी के देशों का समर्थन पहले ही मिल चुका था। प्रस्ताव में माँग की गयी कि—

- (i) अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक आक्रमण की निन्दा की जाए, क्योंकि यह सब अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है।
- (ii) एक मुस्लिम देश पर बड़ी शक्ति का आक्रमण और उसके घरेलू मामले में हस्तक्षेप इस्लामी देशों की दृष्टि में बहुत गम्भीर मामला है।
- (iii) दुनिया के सभी राष्ट्र अफगानिस्तान से तुरन्त बिना शर्त सोवियत संघ और अपने प्रभाव से काम लेकर अफगानिस्तान को सोवियत संघ से खाली करावें।
- (iv) गैरकानूनी काबुल सरकार को कोई मान्यता न दे। उनके सारे निर्णय अवैध माना जायें।
- (v) इस्लामी सम्मेलन से अफगानिस्तान को बाहर कर दिया जाए।
- (vi) काबुल के सारे राजनयिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये जायें।
- (vii) अफगानी जनता को नैतिक सहायता पूरी तरह दिया जाए और स्वाधीनता के लिए संघर्ष में उनकी सहायता की जाए।
- (viii) अफगानिस्तान से सभी तरह का व्यापार समाप्त कर दिया जाए।
- (ix) अफगानिस्तान की जनता मदद के लिए एक बड़ा अरब कोष स्थापित किया जाए।
- (x) इन माँगों को पूरा कराने का काम इस्लामी सम्मेलन के सन्धि को सौंपा जाए।

इन सब बातों को मिलाकर सम्मेलन ने अपनी समाप्ति पर व्यापक प्रस्ताव पास किया। एक ओर सभी इस्लामी देशों की सामूहिक व्यवस्था का सुझाव दिया वहीं दूसरी ओर सभी मुस्लिम देशों ने यह महसूस किया कि इस्लामी देशों पर सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए भी प्रयत्न किये जाने चाहिए।

अन्य सम्मेलन

अफ़ेशियायी जागरण और एकता को सुदृढ़ करने वाले अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए—बेलग्रेड सम्मेलन (1961), काहिरा सम्मेलन (1964), नई दिल्ली सम्मेलन (1966), नुसाका सम्मेलन (1970), जार्ज टाउन सम्मेलन (1972), अल्जीरिया सम्मेलन (1973), अल्जीरिया सम्मेलन (1974), हवाणा सम्मेलन (1975)। ये सभी सम्मेलन गुट-निरपेक्षता के पक्षधर थे और इनका विस्तृत विवेचन गुट-निरपेक्षता सम्बन्धी अध्याय में किया गया है।

अफ़ेशियायी एकता को हानि पहुँचाने वाले कुछ सम्मेलन

एशिया और अफ्रीका के कुछ ऐसे सम्मेलन भी हुए हैं जिनमें अफ़ेशियायी एकता को लाभ पहुँचाने की अपेक्षा हानि अधिक हुई है और आपसी फूट को प्रोत्साहन मिला है। इन सम्मेलनों पर भी एक दृष्टि डालना उपयुक्त होगा।

जद्दा सम्मेलन, 1972

मार्च, 1972 में 31 एशियायी इस्लामी विदेश-मन्त्रियों का यह पाँच दिवसीय सम्मेलन सऊदी-अरब की राजधानी जद्दा में हुआ। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जहर उगला, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। पाकिस्तान ने माँग की कि सम्मेलन की विजयिता में बंगलादेश का उल्लेख न कर 'एक पाकिस्तान' की बात कही जाए, लेकिन सऊदी अरब के शाह फ़ैजल (जिनकी मार्च, 1975 में हत्या कर दी गई) ने माफ़ कह दिया कि बग़दा देश एक 'वास्तविकता' है और इसके सन्दर्भ में ही बात की जानी चाहिए। सम्मेलन में बंगलादेश को मान्यता देने की बात भी उठी, किन्तु नोबिया, जोर्डन, इण्डोनेशिया और मलेशिया ने इसका विरोध किया। वास्तव में यह एक सेदजनक बात थी कि इस्लामी सम्मेलन में बंगलादेश के मुसलमानों के हितों की अपेक्षा की गई। इस्लामी देशों ने बंगलादेश के अपने ही जाति भाइयों को 'बाकिर' समझा और पाकिस्तान के अत्याचारों पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारत-रूसी दोस्ती के सम्बन्ध में भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि तथा कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने बठोर शब्दों का प्रयोग किया।

इस्लामी सम्मेलन का एक उद्देश्य एक नए गुट का निर्माण भी था ताकि समय-समय पर इस गुट के सदस्य मिलकर आपसी हितों पर विचार कर सकें। सम्मेलन में इस बात को मुस्लिम हितों के विरुद्ध बताया गया कि मुस्लिम जगत् में यहूदियों और साम्यवादियों का प्रवेश हो। इस सम्मेलन में यमन और ईराक शामिल नहीं हुए।

कुल मिलाकर यह सम्मेलन एशियायी एकता में दरारें डालने वाला मिट्टा हुआ। स्वयं मुस्लिम देशों के हितों को भी सम्मेलन की कार्यवाही से हानि अधिक पहुँची, लाभ कम हुआ।

इस्लामी शिखर-सम्मेलन, 1974

पाकिस्तान में लाहौर में 22 फरवरी से 24 फरवरी, 1974 तक एक इस्लामी शिखर सम्मेलन हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो

ने अध्यक्षता की। सम्मेलन में 36 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधिमण्डल शामिल हुए। इस सम्मेलन को यद्यपि 'अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी राज्य सम्मेलन' का नाम दिया गया, लेकिन न तो इसका स्वरूप ही अन्तर्राष्ट्रीय था और न इसमें शामिल होने वाले सभी राज्य इस्लामी थे। टर्की, इण्डोनेशिया आदि देशों को भी इसमें आमन्त्रित किया गया था जिन्होंने स्वयं को विधिवत् इस्लामी राज्य घोषित नहीं किया है। यदि सम्मेलन का उद्देश्य धार्मिक था तो भारत सहित उन देशों को आमन्त्रित क्यों नहीं किया गया जहाँ बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में अनेक राज्यों में मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं, किन्तु लाहौर के इस सम्मेलन में केवल 13 अफ्रीकी देश ही सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार यह सम्मेलन अफ्रीका-महाद्वीप के भी सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था।

वास्तव में लाहौर के इस्लामी सम्मेलन का स्वरूप राजनीतिक अधिक था। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि सम्मेलन में भारत अपने यहाँ के सात करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करे। उसे भय था कि ऐसा होने पर इस्लामी राज्यों का मुखिया बनने का उसका स्वप्न पूरा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान का खयाल ऐसा था कि मानों मुस्लिम देशों का अस्तित्व पाकिस्तान के अस्तित्व के साथ जुड़ा हो।

सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए और जो सुझाव दिए गए, वे संकेत रूप में इस प्रकार थे—(i) दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए—एक ने बर्क़ालत में इजरायली सैनिकों की तुरन्त वापसी की माँग की गई; दूसरे में कहा गया कि इस्लामी देश फिलिस्तीनियों के वंश स्थान दिलाने की कोशिश करते हुए इजरायल द्वारा हथियाए गए इलाकों की वापसी के लिए मित्र, सीरिया तथा जोर्डन की पूरी सहायता करें। (ii) पश्चिमी एशिया तथा तेल आदि विषयों पर भी प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। मित्र के राष्ट्रपति अन्वर सादत और मलजीरिया के राष्ट्रपति बूर्मदीएन का यह सुझाव महत्वपूर्ण था कि इस्लामी सम्मेलन को तेल-विहीन विकासशील देशों के लिए सहायता की रकम निर्धारित कर देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तेल के वर्तमान भावों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। (iii) लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी ने एक तीन स्तरीय पद्धति का सुझाव दिया—औद्योगिक राष्ट्र वर्तमान भावों से तेल खरीदे, जबकि तीसरी दुनिया और इस्लामी देशों को उनके आकार और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार रियायती भुत्थ पर तेल दिया जाए। (iv) उगाण्डा के राष्ट्रपति ईदी अमीन ने सुझाव दिया कि ईराक और ईरान में सामान्य सम्बन्ध कायम करने के लिए इस्लामी देशों का एक सद्भावना आयोग दोनों देशों में भेजा जाए। (v) ईदी अमीन ने मुस्लिम देशों से यह भी अनुरोध किया कि वे इजरायल, रोडेशिया और दक्षिण-अफ्रीका के विमानों को अपने हवाई अड्डों पर उतरने की आज्ञा न दें।

लाहौर के इस्लामी मिलन-सम्मेलन से तीन घाने अच्छी तरह स्पष्ट हो गईं—(1) पाकिस्तान का भारत-विरोधी खयाल और भारतीय मुसलमानों को 'काफिर' समझना, (2) मुस्लिम देशों की आपसी फूट और एशिया तथा अफ्रीका के

अनेक मुस्लिम देशों का इस्लामी सम्मेलन में भाग न लेना, एवं (3) अनेक राष्ट्रों का आचरण जो कि अफेगिनायी एकता में दरारें डालने वाला था।

इस्लामी सम्मेलन (जनवरी, 1981)

सऊदी अरब की ग्रीष्मकालीन राजधानी तैफ में तीसरा इस्लामी सम्मेलन चार दिन तक खुले और गोपनीय अधिवेशनों के बाद 28 जनवरी, 1981 को सम्पन्न हुआ। अन्ततः पारित प्रस्ताव बहुत कुछ वही थे जिनकी चर्चा पहले से थी—मसलन, यरूशलम को अरब सम्भाग को इजरायली कब्जे से मुक्त कराना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इजराइल का आर्थिक बहिष्कार, अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी और मुस्लिम देशों को आर्थिक उन्नति के लिए एक सहायता कोष की स्थापना। ईराक-ईरान सघर्ष, जो कि एक तरह से घरेलू मामला था, उसके लिए सिरदर्द ही बना रहा।

दरअसल, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों का नेक इरादा है कि धार्मिक आधार पर मुस्लिम देशों को एकजुट करके एक इस्लामी गुट बनाया जाए। पाकिस्तान का तर्क है कि यदि फारम की खाड़ी के देश सुरक्षा के लिए महती शक्तियों के पाम अपने को गिरवी रखने से बचे रह सकें तो इस क्षेत्र के देश अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं। यह बात अन्य देशों के मन में रही हो, तो भी वे इसे बहुत सीमित अभिव्यक्ति दे पायें—केवल इतना कहा जा सका कि मुस्लिम देश किसी भी गुट में शामिल न हो, यानी गुट-निरपेक्ष देशों का अनुसरण करें क्योंकि मुस्लिम देशों की विरादरी में मतभेद बहुत है और मिस्र को कंश्च डेविड समझौते के कारण बहिष्कृत करने की तैयारी थी इसलिए मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति सादात के तैफ आने का स्वागत ही नहीं था। ईरान के नेता ईराक की शिरकत के कारण नहीं आए। सामन्ती विचारधारा के विरोधी दक्षिण यमन और सोवियत समर्थक सीरिया ने अफगान सम्बन्धी प्रस्ताव को अपनी सहमति नहीं दी। सऊदी अरब को ईराक की 'उग्र प्रगतिशीलता' और अरबों का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा फूटी आँखों भी नहीं मुहगती। लीबिया द्वारा चंड के विलय की कोशिश के व्यापक विरोध के कारण गद्दाफी ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया इसलिए केवल उन्हीं मसलों पर प्रस्ताव पारित किए गए जिन पर अधिकांश या सब देश सहमत हो सकते थे। इनकी भाषा में गरमजोशी तो थी मगर दुष्चक्र में फँसे तीसरी दुनिया के अन्य देशों के स्वर की तरह खोललापन भी था।

इस्लामी सम्मेलन के आयोजकों ने ध्यान रखा कि उनके एकता प्रयासों को गलत न समझा जाए। इसलिए इन देशों के विदेश मन्त्रियों का कहना था कि हमारे एकता के प्रयास से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को, जो इस्लामी विरादरी से भी अधिक विभाजित है, सहायता मिलेगी।

सम्मेलन के बाद प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्ति में अरबी यरूशलम को मुक्त कराने के लिए एक योजना का उल्लेख था। यह तय पाया गया कि मुस्लिम देश इजरायल की अर्थ-रचना को कमजोर करने के लिए अपने आर्थिक और प्राकृतिक

साधनों का हथियार की शक्ति में इस्तेमाल करेंगे। ये देश यह भी कोशिश करेंगे कि यरूशलेम का अरब सम्भाग ही नहीं, सभी अधिकृत क्षेत्र इजरायल के कब्जे से मुक्त हो और अन्तर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा बने जो फिलीस्तीनियों और फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अनुकूल हो। इस सन्दर्भ में 'जेहाद' शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ तात्पर्य संघर्ष से था। इस्लामी शिखर सम्मेलन ने संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद् का 242वाँ प्रस्ताव यह कहकर रद्द कर दिया कि वह फिलीस्तीनी अरबों के अधिकारों के विरुद्ध है, यद्यपि अभी तक इसे समाधान का बुनियादी आधार माना जाता था। इस प्रस्ताव का आग्रह था कि इजरायल अरबों के अधिकृत क्षेत्र खाली कर दे और पश्चिमेशिया के हर देश को सरक्षणीय सीमा पर काबिज रहने का पूरा अधिकार हो। दूसरा मुख्य प्रस्ताव अफगानिस्तान सम्बन्धी था। अफगानियों के आत्मनिर्णय का अधिकार स्वीकारते हुए शिखर सम्मेलन ने विदेशी सेनाओं की वापसी की माँग की और कहा कि इस समस्या का राजनीतिक समाधान खोजा जाना चाहिए। अफगानिस्तान सम्बन्धी तदर्थ समिति में सगठन के प्रतिनिधि के अलावा गिनी, ईरान, पाकिस्तान और ट्यूनीसिया के प्रतिनिधि हैं। समिति ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कुतुबुद्दीन से समस्या का युक्तिमय समाधान निकालनेका अनुरोध किया।

फिलीस्तीनियों और अफगानिस्तान की समस्याएँ प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई से तात्लुक रखती हैं, बल्कि उन्हीं के दिए हुए उपहार हैं। इन पर प्रस्ताव पास करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है उन्हें लागू करना या कुछ कर गुजरना।

सम्मेलन द्वारा स्थापित इस्लामी विकास कोष की, जिसकी आरम्भिक पूँजी 3 अरब डॉलर (24 अरब रु.) होगी, सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने साधनों का इस्तेमाल कैसे करता है। एक-तिहाई रकम सऊदी अरब ने देने का वायदा किया और अरब अमीरात भी कुछ धनराशि देने की राजी हो गया। यह धनराशि सदस्य देशों का व्यापार बढ़ाने और जहाजरानी कम्पनियों के साधनों का माभी जलीरा बनाने पर भी खर्च की जाएगी।

अल्जीरिया का स्वाधीनता-संग्राम

अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया ने फ्रांस के विरुद्ध जो लम्बा स्वाधीनता-संग्राम लड़ा वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि—(1) अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद का सबसे निरंकुश और दर्दनाक रूप अल्जीरिया में देखने को मिला, (2) अल्जीरिया का संघर्ष दुनिया के दूमरे देशों के स्वाधीनता-संग्रामों के लिए एक प्रकाश बन गया, एक (3) इस संग्राम ने पुनः इस बात की पुष्टि कर दी कि ध्वेन जातियों से टक्कर लेकर उन्हें नाकों बने चबवाए जा सकते हैं।

अल्जीरिया पर फ्रांस का अधिकार सन् 1830 में स्थापित हुआ था। फ्रांसीसियों ने यहाँ बसकर अल्जीरिया का हर प्रकार से शोषण किया। अल्जीरिया-वासियों के प्रत्येक विरोध का फ्रांस सदैव कठोरतापूर्वक दमन करता रहा। उन्हें

शान्त करने के लिए कालान्तर में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिया गया, लेकिन अल्जीरियावासी इससे सन्तुष्ट नहीं हुए। 1 जुलाई, 1951 को उन्होंने एक राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण किया जो 'राष्ट्रीय स्वाधीनता मोर्चा' (Front of National Liberation--F N L) के नाम से विख्यात हुआ। मोर्चे ने 1 नवम्बर, 1954 से स्वाधीनता-सर्घ्व छेड़ दिया जो लगभग 7 वर्ष तक चला। इस युद्ध में लगभग 4,00,000 व्यक्ति मारे गए। इनमें से लगभग 2,00,000 असैनिक अल्जीरियायी मुसलमान, 1,60,000 स्वतन्त्र अल्जीरियायी सरकार के सैनिक, 18,000 फ्रांसीसी सैनिक तथा 2,000 गोरे अल्जीरियायी निवासी थे। अल्जीरियायी राष्ट्रवादी इस सरया को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि फ्रांसीसी सेनाओं ने कम से कम दस लाख अल्जीरियायी मौत के घाट उतार दिए। युद्ध-बन्दी के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। फ्रांस के दुराग्रही रुख के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी युद्ध-विराम के लिए कुछ नहीं किया जा सका। जून, 1958 में जनरल डिगॉल विस्तृत अधिकारों सहित फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने। उन्होंने फ्रांस की जनता को यह वचन दिया कि वे अल्जीरिया की समस्या को शीघ्र ही निपटा देंगे।

सितम्बर, 1959 में फरहत् अब्दास के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता मोर्चे ने काहिरा में एक समानान्तर सरकार की स्थापना की जिसे चीन द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दी गई। परिस्थितियों से बाध्य होकर 4 नवम्बर, 1960 को जनरल डिगॉल ने अल्जीरिया को स्वतन्त्रता देने की घोषणा की। उन्होंने 'अल्जीरिया, अल्जीरिया वालों के लिए' के प्रश्न पर जनमत कराने का प्रस्ताव रखा, किन्तु फरहत् अब्दास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा कर अपने अनुयायियों की मतदान में भाग न लेने का आदेश दिया। फिर भी 8 जनवरी, 1961 को जनमत-संग्रह हुआ और फ्रांस तथा अल्जीरिया दोनों में विशाल बहुमत ने डिगॉल की अल्जीरिया सम्बन्धी नीति का समर्थन किया। 27 मार्च, 1961 को फ्रांस और अल्जीरिया द्वारा शान्ति-वार्ता में भाग लेने की सहमति की घोषणा की गई किन्तु अगले ही माह अप्रैल, 1961 में इस आगामी शान्ति-वार्ता के विरुद्ध जनरल साला और अन्य जनरलों के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने अल्जीरिया में विद्रोह कर दिया। डिगॉल ने विद्रोहियों के खिलाफ तेजी से कठोर कदम उठाए। जनरल साला गायब हो गया और उसने एक गुप्त संगठन (OAS) की स्थापना कर ली।

20 मई, 1961 को फ्रांस और अल्जीरिया में शान्ति-वार्ता आरम्भ हुई, किन्तु तुरन्त ही भंग हो गई। शान्ति-वार्ता की आख-मिचोनी चपती रही। जनवरी, 1962 में श्री ए. एम. आतकबादियों ने अल्जीरिया भर में मुसलमानों पर आक्रमण किया, मुसलमानों ने भी जवाबी हमले किए और दोनों पक्षों के सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। फरवरी, 1962 में शान्ति-वार्ता में प्रगति हुई और अगस्त में 18 मार्च, 1962 को युद्धबन्दी के बाद दोनों पक्षों (अल्जीरिया और फ्रांस) ने बीच गमभीरता की घोषणा की गई। जुलाई, 1962 को अल्जीरिया स्वतन्त्र हो गया और

इस तरह एक महान् स्वतन्त्रता-संग्राम का अन्त हुआ। 20 सितम्बर, 1962 को अल्जीरिया के एकदलीय चुनावों में बेनबेला गुट की विजय हुई। विरोधी गुट बेनबेदा का था। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि गृह-युद्ध की आशंका होने लगी, लेकिन अन्त में दोनों नेनाग्रो में समझौता हो गया।

रूस की अफ्रीकी नीति

अफ्रीका में पश्चिमी यूरोप और पूर्व यूरोपीय देशों के हस्तक्षेप के आरोप अफ्रीकी एशियायी देशों के पत्र ही नहीं बल्कि पश्चिम और पूर्व यूरोपीय देशों के पत्र भी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के प्रमुख समाचार पत्र एक दूसरे पर अफ्रीका के आन्तरिक मामलों में दखल देने का आरोप पिछले काफी समय से लगाते रहे हैं। लेकिन इसपर अब से अफ्रीकी देशों की आपसी लड़ाइयाँ और जोर पकड़ गई हैं इन देशों के आरोप-प्रत्यारोप भी व्यापक रूप से रहे हैं। प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाचारपत्र समान्द ने 1978 के एक सम्पादकीय लेख में सोवियत संघ की अफ्रीकी नीति की जो विवेचना की है वह आज के सन्दर्भ में भी महत्वपूर्ण है।

कुछ दिनों से सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों पर अफ्रीका के आन्तरिक मामलों, विशेषकर जेयरे, में फ्रांस के हस्तक्षेप का प्रचार तेज कर दिया। वैसे तो सोवियत संघ का यह प्रचार बहुत समय से है लेकिन अब सोवियत संघ यह प्रचार आयद इमनिए और भी जोरों से कर रहा है कि अफ्रीका में उनकी मौजूदगी की तरह दुनिया का ध्यान न जाए।

सोवियत संघ का दावा है कि अफ्रीकी देशों के आन्तरिक मामलों में सोवियत संघ और क्यूबा का हस्तक्षेप आज बिल्कुल स्पष्ट है लेकिन यह बात सोवियत संघ पर अधिक लागू हो रही है। अफ्रीका के प्रति सोवियत संघ की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। पहले अफ्रीकी देशों में स्वाधीनता सघर्ष को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था लेकिन अब अफ्रीकी देशों की जनता अपने ही शाराकों के विरुद्ध आर्थिक स्वाधीनता के लिए जो सघर्ष कर रही है उसमें सोवियत संघ खुले तौर पर उनका साथ दे रहा है। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि अभी तब तो औपनिवेशिक देशों के विरुद्ध अफ्रीकी देशों के स्वाधीनता सघर्ष या समर्थन सोवियत संघ कर रहा था लेकिन अब यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रगतिशील कहे जाने वाले उन लोगों का समर्थन कर रहा है जो स्वाधीनता के बाद अपने देशों की सरकारों से आर्थिक सुधारों की माँग कर रहे हैं। एक प्रकार से यह स्वाधीन अफ्रीकी राष्ट्रों में सरकारों के विरुद्ध जन सघर्ष को प्रोत्साहन देना है। स्पष्ट है अफ्रीका के प्रति सोवियत संघ की इस नीति का अन्त अफ्रीकी देशों और साथ ही साथ समूचे विश्व की राजनीति पर भी पड़ेगा। लेकिन सोवियत संघ अभी भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह अफ्रीकी देशों के आन्तरिक सघर्ष में तथाकथित प्रगतिशील शक्तियों का साथ दे रहा है पर कुछ घटनाओं से यह बात अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। सन् 1960 के दशक में अफ्रीकी देशों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध

स्वाधीनता संघर्ष में सोवियत संघ के समर्थन को स्वयं अफ्रीकी देशों की जनता ने कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया था। परिणामस्वरूप स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सोवियत संघ की सरकार ने उन सरकारों को समर्थन देना शुरू कर दिया था जो वहाँ स्वाधीनता प्राप्ति के बाद स्थापित हुई थी। इस प्रकार के समर्थन से भले ही अफ्रीकी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को नुकसान पहुँच रहा था लेकिन सोवियत संघ ने उस समय यही उचित समझा कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद की सरकारों का ही समर्थन किया जाए जब कुछ स्वाधीन अफ्रीकी देशों की सरकारों ने साम्यवादी विचारधारा के नेताओं और छात्रों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ शुरू कर दीं तो सोवियत संघ की नीति में परिवर्तन आना ही था। सोवियत संघ यह भली प्रकार समझ गया था कि अफ्रीकी देशों में स्वाधीनता के बाद जो नई सरकारें हों वे राजनैतिक स्थिरता नहीं ला सकेंगी इसलिए उसने इन देशों में एकदलीय प्रणाली की साम्यवादी व्यवस्था की नींव डालने की कोशिश की। उद्देश्य था कि नवोदित स्वाधीन अफ्रीकी देशों में असन्तोष का लाभ उठाकर साम्यवाद की स्थापना की जाए।

अब यह दौर भी समाप्त हो गया। बहुत से अफ्रीकी देशों ने स्वाधीनता प्राप्त कर ली है और वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने समाज और शासन व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। अब सोवियत संघ के सामने केवल यह काम रह गया है कि वह अफ्रीकी देशों पर आर्थिक सुधारों के लिए दबाव न डाले लेकिन इन देशों में अमेरिका की नीतियों को विफल बना दे। इसके लिए सोवियत संघ जो कुछ कर रहा है उसका इतना महत्त्व नहीं है जितना कि इस बात का कि अफ्रीका में यह क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है? आज उत्तर से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक सभी राष्ट्र भ्रान्तरिक संघर्ष की लपेट में हैं। इन भ्रान्तरिक संघर्षों की दिशाएँ अलग-अलग हैं। क्या सोवियत संघ इन संघर्षों में ऐसे तत्वों को अपना समर्थन देना चाहता है जो वहाँ आर्थिक असन्तोष का लाभ उठाकर समाजवाद लाने के लिए प्रयत्नशील है? अफ्रीकी एकता के प्रति भस्करा का रक्त समय-समय पर बदलता रहा है। एक ओर तो सोवियत संघ अफ्रीकी एकता संगठन को अफ्रीकी जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक मानता है और दूसरी ओर वह ऐसे तत्वों को भी समर्थन दे रहा है जो इस प्रकार की एकता में बाधा है। निश्चय ही सोवियत संघ अफ्रीकी देशों में वहाँ के ऐसे तत्वों के बीच भेद-भाव करता है जो देश की प्रगति के लिए समाजवाद चाहते हैं और दूसरे जो पूँजीवाद का रास्ता अस्तिवार करके देश की प्रगति चाहते हैं। स्पष्ट है कि सोवियत संघ का समर्थन समाजवाद लाने वाले तत्वों को हो जाएगा। अभी हाल ही में सोवियत समाचार-पत्र 'प्रवदा' ने अपने एक सम्पादकीय लेख में लिखा था कि अफ्रीका में प्रगति की प्रक्रिया एक नया रूप ले रही है। पत्र का कहना था कि जो भी देश स्वाधीनता प्राप्त कर लेता है उसे आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता की ओर बढ़ना ही होता है जिसका मतलब यह है कि वह अपनी पर्य-व्यवस्था को पूँजीवादी एकाधिकार में मुक्त करे। यह तभी हो सकता है जब कि वह अपने यहाँ उत्पादन और व्यापार के माध्यमों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण

कर दे क्योंकि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अफ्रीकी देशों के लिए किसी भी हालत में उपयुक्त नहीं है।

‘प्रावदा’ के इस लेख से अफ्रीका के प्रति सोवियत नीति का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। यह नवोदित स्वाधीन अफ्रीकी देशों की सरकारों के लिए चिन्ता का विषय है। इन सरकारों को सोवियत संघ ने प्रतिश्रियावादी सरकारों की सजा दी है। सभी जानते हैं कि सोवियत संघ को पश्चिमेशिया में अपना प्रभाव जमाने के प्रयत्नों में मुँह की खानी पड़ी है। इसलिए अब अफ्रीका में सोवियत संघ ने प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने का नया मिलतिला शुरू कर दिया है। उभरअफ्रीका में चीनियों की गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं जिसका असर सोवियत संघ के इन प्रयत्नों पर निश्चय ही पड़ेगा। आज सोवियत संघ की अफ्रीकी नीति विश्व में तनातनी कम करने के प्रयत्नों में उसके योगदान की घोषणा के विरुद्ध है।

अफ्रीका के प्रति पश्चिमी यूरोपीय देशों की स्पष्ट नीति की माँग

अफ्रीका के प्रति पश्चिम यूरोपीय देशों की स्पष्ट नीति की माँग पश्चिमी यूरोपीय समाचार-पत्रों में ही की जा रही है। यूरोपीय समुदाय के देशों में इस प्रश्न को लेकर कुछ मतभेद प्रवर्धित हैं। इसका आभास पश्चिम यूरोपीय समाचार-पत्रों की टिप्पणियों से ही मिलता है। पश्चिमी जर्मनी के एक प्रमुख समाचार-पत्र फ्रैंकफुर्त्तर अन्गेमाइने स्टाईटुंग के कुछ अर्थ पूर्व के एक सम्पादकीय लेख के अनुसार—

“पश्चिमी जर्मनी का युवा वर्ग आज उपनिवेशवाद और जाति भेद-भाव के जितना विरुद्ध है उतना पहले कभी नहीं रहा, लेकिन खेद है कि पुरानी पीढ़ी के लोग अभी भी दक्षिण अफ्रीका में शोरी के भविष्य को लेकर चिन्तित है। फिर पश्चिमी जर्मनी सहित अन्य यूरोपीय देशों के वहाँ व्यावसायिक हित भी हैं जिनकी रक्षा के लिए इन देशों की सरकारें बहुत उत्सुक हैं। अभी भी पश्चिमी यूरोप के अनेक देश दक्षिण अफ्रीका से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करते हैं। अफ्रीका के प्रति पश्चिमी जर्मनी की नीति केवल विदेश विभाग तक ही सीमित है। अफ्रीकी देशों के लिए विकास सहायता में वृद्धि की आवाज अभी भी गम्भीरतापूर्वक सोची नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारे देशों को अफ्रीका के प्रति अपनी नीति तो स्पष्ट करनी ही है साथ ही साथ उसे अपने मित्र देशों की नीतियों के साथ तालमेल बिठाने का काम भी करना है। हम जानते हैं कि अफ्रीका को उसके विकास में सहायता देने का काम जर्मनी ही अकेले नहीं कर सकता अन्य देशों को भी इसमें सहयोग करना है। उभर अफ्रीकी देशों का पश्चिमी यूरोपीय देशों के प्रति अविश्वास अभी भी बना हुआ है क्योंकि इनमें से बहुत से देश उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते रहे हैं।”

अभी हाल ही में अफ्रीका के लिए सहायता में कुछ यूरोपीय देशों ने जो समान रकबा अपनाया उससे अन्धे नतीजे निकले हैं। पहला तो यही कि अफ्रीका में यूरोप को सोवियत संघ और अमेरिका जितना खतरनाक नहीं माना जा रहा है। यूरोपीय

समुदाय के देशों ने अफ्रीका में बड़े देशों के प्रभाव क्षेत्र बनाने के प्रयत्नों के विरुद्ध जो भी आवाज उठाई है उसके कारण अफ्रीकी देशों में यूरोप की छवि उभरी है। समुदाय के 9 सदस्य देशों को अमेरिका के साथ मिल कर अफ्रीका के प्रति अपनी नीति को उदार बना कर आवश्यक परिवर्तन लाने हैं।

यह ठीक है कि यूरोपीय समुदाय के भीतर ही अफ्रीकी देशों के प्रति नीति के प्रश्न को लेकर कुछ मतभेद हैं लेकिन इन मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। भले ही समुदाय के कुछ देश ही समान नीति पर सहमत हों। पर परिवर्तन और स्पष्टता आवश्यक है। इस प्रश्न पर फ्रांस पश्चिमी जर्मनी के साथ हो सक्ता है क्योंकि फ्रांस इस समय अफ्रीका में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पश्चिमी जर्मनी की तरह फ्रांस भी मानता है कि जहाँ तक सम्भव हो अफ्रीकी देशों को द्विपक्षीय आधार पर विकास सहायता जारी रखनी चाहिए लेकिन समुदाय के अधिकाधिक देश इसमें सम्मिलित हो तो और भी अच्छा है। सहायता में मानवीय आधार और शान्ति प्रयत्नों की प्रमुख स्थान मिलना चाहिए साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी देश पर विकास सहायता थोपी न जाए। पश्चिमी जर्मनी, विकास सहायता के अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर यदि उस पर यह आरोप लगाया जाता रहे कि वह दक्षिण अफ्रीका के साथ परमाणु शक्ति के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है तो उसे सहायता देने से इन्कार करने का पूरा अधिकार है। दरअसल विकास सहायता में पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय समुदाय के देशों का उद्देश्य होना चाहिए कि अफ्रीकी देशों को अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखने और राजनैतिक स्थिरता लाने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाए। पश्चिमी जर्मनी ने तो आपसी बातचीत द्वारा विकास सहायता का अपना कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें किसी बल-प्रयोग की बात नहीं है। हमने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि पश्चिमी और पूर्वी यूरोपीय देशों के आपसी भगड़े अफ्रीकी देशों के विकास में रुकावट नहीं बनने चाहिए। हम हमेशा ही इस समूचे क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र बनाने के विरुद्ध रहे हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि व्यापार बढ़ा कर तथा अफ्रीकी देशों में व्यावसायिक हितों की रक्षा करके परस्पर सम्बन्ध और सुदृढ़ बनाए जाएँ। अफ्रीका के प्रति नीति का निर्धारण करते समय हमारे देश को तथा अन्य यूरोपीय देशों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद-भाव धीरे-धीरे समाप्त हो और वहाँ के अफ्रीकी बहुसंख्यक अपने देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बराबर के साझेदार बनें। अन्ततः हमारा उद्देश्य दक्षिणी अफ्रीका के लोगों को उनके नागरिक अधिकार दिलवाना है। बहुसंख्यक शासन स्थापित करते ही यह हो सकता है। यह ठीक है कि दक्षिणी अफ्रीका का सर्वप्रधान भविष्य वहाँ के अपने लोगों के हाथों में है लेकिन जातिभेद जैसी बुराईयों समाप्त करने में सहायक होना हमारा एक प्रकार से कर्तव्य है। दक्षिणी अफ्रीका में अभी भी जर्मन फर्मों की काफी पूंजी लगी हुई है लेकिन प्रयत्न यह होना चाहिए कि अब वहाँ जर्मनी की निजी फर्मों और पूंजी न लगाएँ।

एशिया और अफ्रीका में विदेशी शक्तियों की स्थिति पर आन्द्रेई प्रोमिको का संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन, 1978 में भाषण

एशिया और अफ्रीका में विदेशी शक्तियों और सोवियत संघ की स्थिति पर सोवियत विदेश मंत्री श्री प्रोमिको ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितम्बर 1978 के अपने भाषण में जो प्रकाश डाला वह अच्ययन योग्य है। अक्टूबर 1978 की सोवियत भूमि के अनुसार—

प्रोमिको ने कहा, अनेक वर्षों और दशकों से विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप एशिया के जनपण इस बात के बारे में चिन्तित रहे हैं कि उनके महाद्वीप में शान्ति एवं सुरक्षा की तथा विकास एवं प्रगति के अवसर को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि इस समस्या के समाधान की कुञ्जी बिना किसी भ्रमवाद के सभी एशियाई राज्यों द्वारा संयुक्त कार्यवाहियाँ हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान परिस्थितियों में जबकि एशिया में स्थिति के विकास में कुछ खतरनाक संकेत प्रकट हो रहे हैं, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एशिया के देशों में यह अनुभूति अधिकाधिक बन रही है कि एशियाई राज्यों के बीच सड़क-झगड़े, उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप और उन पर खुलेआम दबाव डालने तथा उन्हें एक-दूसरे से लड़ने के प्रयत्नों के स्थान पर स्थाई शान्ति स्थापित होनी चाहिए।

इस दृष्टि से संयुक्त वियतनाम की स्थापना का बहुत अधिक महत्त्व है, जिसे अपनी धरती से आश्रामकी की खदेड़ भगाया और अब शान्तिप्रिय नीति का पालन कर रहा है। आन्द्रेई प्रोमिको ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से सोवियत संघ फिर वियतनाम के साथ अपनी एकजुटता घोषित करता है और इस बात पर तल देता है कि उस पर किसी भी प्रकार के प्रभुत्ववादी दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आन्द्रेई प्रोमिको ने कहा, सोवियत संघ एशिया के राज्यों के साथ अच्छे सम्बन्धों का परोक्षार है, जो हमारे साथ आपसी समझ और अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों के इच्छुक है। हम बहुत से मामलों में अनेक वर्षों से इसी प्रकार के सम्बन्ध अधिसंख्याक एशियाई राज्यों के साथ बनाए चले आ रहे हैं। समान और परस्पर लाभदायक सहयोग के हितों के अलावा जो आपसी सम्मान, सम्प्रभुता के बठोर परिपालन और एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्तों पर आधारित है। सोवियत संघ इन देशों के साथ एशिया में शान्ति व सुरक्षा के दृढीकरण के प्रति समान चिन्ता और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद की शक्तियों की साजिशों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष में भागीदार है।

सोवियत-भारतीय सम्बन्ध विभिन्न सामाजिक प्रणालियों वाले राज्यों के बीच बहुमुखी मिश्रतापूर्ण सहयोग और शान्तिपूर्ण सहजीवन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये सम्बन्ध जो अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों की दीर्घकालिक परम्परा से सम्बद्ध

हैं, 1971 की शान्ति, मित्रता व सहयोग की सन्धि की दृढ़ आधारशिला पर उत्तरोत्तर विवसित हो रहे हैं। आन्द्रेई ग्रोमिको ने कहा, ये सम्बन्ध दोनों देशों के बुनियादी हितों की पूर्ति करते हैं और एशियाई महाद्वीप तथा सम्पूर्ण विश्व में शान्ति के लिए महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावी कारक हैं।

आन्द्रेई ग्रोमिको ने कहा, यदि सभी एशियाई राज्यों के साथ 'सोवियत सघ' के इसी प्रकार के सम्बन्ध नहीं हैं तो इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। यह जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर है जो सोवियत सघ के सम्बन्ध में वद्वृत्तापूर्वक शत्रुतापूर्ण नीति का, ऐसी नीति का पालन करते हैं जो सामान्य रूप से शान्ति के ध्येय के लिए ही शत्रुतापूर्ण है। यह जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर है जो प्रभुत्ववादी उद्देश्यों का पालन करते हुए दूसरों पर प्रभुत्ववादी होने का आरोप लगाते हैं और जो तथ्यों के प्रतिकूल आचरण करते हैं।

आन्द्रेई ग्रोमिको ने जोर देकर कहा कि जापान जिस नीति का पालन कर रहा है वह भी सुदूर पूर्व में और प्रशान्त महासागर में शान्ति के हित में नहीं है। दुर्भाग्यवश, इसकी नीति में कुछ अशान्तिजनक प्रवृत्तियाँ प्रकट हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह देश अन्ततः ऐसे मार्ग पर चल पड़े, जिसके कारण अतीत में अन्य जनगण को नाना प्रकार की मुसीबतें भेलनी पड़ी थी और जिसने जापान को विनाश के गर्त में डाल दिया था। आन्द्रेई ग्रोमिको ने कहा, "मैं इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करता चाहूँगा लेकिन इस सबकी ओर गम्भीर रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि हमारी इस चिन्ता में और अनेक सहभागी हैं।"

जापान के सम्बन्ध में सोवियत नीति पहले भी सिद्धान्तनिष्ठ रही है और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। सोवियत सघ इस देश के साथ अच्छे सम्बन्धों की हिमायत करता है, तो भी, आन्द्रेई ग्रोमिको ने जोर दिया, जापान की ओर उचित कदम उठाए जाने की अपेक्षा की जाती है।

आन्द्रेई ग्रोमिको ने अफ्रीका में विद्यमान स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, आज अफ्रीका महाद्वीप की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस महाद्वीप में, जिसकी आबादी लगभग 40 करोड़ है, बेदारी और बेचैनी है। नवस्वतन्त्र राज्यों के अम्युदय की प्रक्रिया जारी है और उपनिवेशवाद की अन्तिम जजीरों को तोड़ कर फँका जा रहा है लेकिन रोडेशिया, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में अभी भी औपनिवेशिक शासन कायम है, जहाँ नस्ली भेदभाव के अत्यन्त बर्बर स्वरूप प्रचलित हैं।

आन्द्रेई ग्रोमिको ने कहा, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों की स्थिति के सम्बन्ध में सोवियत सघ तथा दूसरे समाजवादी राज्यों की नीति पर लक्ष्य लगाने के लिए न जाने क्या कुछ कहा जाता है और न जाने कितना कागज बर्बाद किया जाता है। लेकिन यह सब बरबोस क्यों रहा है? वे ही लोग जो उपनिवेशवाद और नस्लवाद के

अवशेषों से चिपके हुए है। यह जानते हुए कि इस प्रकार की हरकतें जन-प्रिय नहीं हैं। वे जनगण को धोखा देने के लिए अपनी नवउपनिवेशवादी कामवाहियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह धोखा ज्यादा दूर तक उनका साथ नहीं देगा। जनगण स्वयं ही यह देख लेगे कि कहीं सच्चाई है और वहाँ झूठ है।

आन्द्रेई ग्रोमिको ने बल देकर कहा कि अफ्रीका महाद्वीप में उपनिवेशवाद और नस्लवाद को पूर्ण रूप से और अन्तिम रूप से मिटा दिया जाना चाहिए।

सोवियत विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा, हमने उन लोगों के साथ जो राष्ट्रीय स्वाधीनता और सामाजिक प्रगति के लिए लड़ रहे हैं अपनी सहानुभूति न तो कभी छिपाई है और न अब छिपाते हैं। लेकिन हम न तो अफ्रीका से और न ही अन्य महाद्वीपों के विकासमान देशों में अपने लिए किसी लाभ के तलबगार हैं। सोवियत संघ को राजनीतिक प्रभुत्व, रियायती अथवा सैनिक अड्डों की चाह नहीं है।

“अफ्रीका अथवा विश्व के अन्य क्षेत्रों के राज्य जब आक्रमण—हम यह दोहरा दें कि आक्रमण अथवा सशस्त्र आक्रमण को विफल करने के लिए सहायता माँगते हैं तो उन्हें यह अधिकार है कि वे अपने मित्रों के समर्थन पर भरोसा रखें।”

आन्द्रेई ग्रोमिको ने कहा, “ऐतिहासिक विकास के वस्तुनिष्ठ, अपरिहार्य नियम विजयी होंगे। वह दिन दूर नहीं जब दक्षिण अफ्रीका की जनता के लिए भी स्वाधीनता का प्रभाव उदित होगा और जब सभी अफ्रीकी भूमि, उसकी एक-एक इंच भूमि स्वाधीन होगी।”

दक्षिण रोडेशिया (अब स्वाधीन जिम्बाब्वे) का संकट

जम्बेजी नदी तथा उत्तरी ट्रांसवाल के मध्य स्थित दक्षिण रोडेशिया (जो 18 अप्रैल 1980 को स्वाधीनता प्राप्त कर जिम्बाब्वे नाम धारण कर चुका है) अफ्रीका का एक देश है। इस देश का क्षेत्रफल 390 हजार वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 60 लाख है। इसमें 40 लाख से ऊपर अफ्रीकी हैं, लगभग 2 लाख यूरोपीय हैं और शेष अन्य। दक्षिण रोडेशिया का, जिसकी राजधानी सेलिसबरी है, मूल विवाद यह था कि यहाँ की गोरी सरकार बहुसंख्यक अफ्रीकियों को देश के शासन में सामीदार नहीं बनाना चाहती थी और राष्ट्रवादी अफ्रीकी इस बात के लिए निरन्तर संघर्ष कर रहे थे कि दक्षिण रोडेशिया का शासन अफ्रीकियों के हाथ में हो सके औरों की प्रभुसत्ता का अन्त हो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1953 में ब्रिटेन ने उत्तरी रोडेशिया (जिसका शासन उसने 1924 में अपने हाथ में लिया था), दक्षिण रोडेशिया और न्यासालैण्ड (रोडेशिया का पड़ोसी देश जिन पर ब्रिटेन ने 1891 में अधिकार किया था) को मिलाकर ‘मध्य अफ्रीका संघ’ की स्थापना की। उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैण्ड की जनता ने संघ का विरोध किया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इस संघ में अफ्रीकी लोगों की बहुलता थी, लेकिन निर्वाचन-प्रणाली इस प्रकार की थी कि कोई अफ्रीकी चुनाव में सड़ा

नहीं हो सकता था। अन् अफ्रीकियों में असन्तोष बढ़ता गया और धीरे-धीरे राष्ट्रवाद की लहर इतनी प्रबल हो गयी कि ब्रिटेन अधिक समय तक जनता की अपेक्षा नहीं कर सका तथा 1963 में अफ्रीकी सघ भग हो गया। न्यासालैण्ड और उत्तरी रोडेशिया स्वतन्त्र हो गए। आजादी के बाद उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया कहलाने लगा और न्यासालैण्ड का नाम मलावी रखा गया। दक्षिण रोडेशिया अब भी ब्रिटिश सम्प्रभुता के अधीन रहा और इयान स्मिथ वहाँ के नये प्रधानमन्त्री बने।

प्रधानमन्त्री इयान स्मिथ ने ब्रिटेन को धमकी दी कि वह दक्षिण रोडेशिया को स्वतन्त्र कर दे अन्यथा दक्षिण रोडेशिया की सरकार अपनी ओर से स्वतन्त्रता की घोषणा कर देगी। ब्रिटेन ने कहा कि स्वतन्त्रता तभी दी जा सकती है जब (1) सब अफ्रीकी लोगों को भूतधिकार प्राप्त हो, एवं (2) गोरों लोगों के लिए सुरक्षित किए गए विशेष प्रदेशों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। स्मिथ सरकार ने ब्रिटिश शर्तों को प्रमान्य ठहराते हुए 11 नवम्बर 1965 को दक्षिण रोडेशिया की एकपक्षीय स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी जिससे रोडेशिया सम्बन्धी महान् माविधानिक संकट पैदा हो गया। अनेक राजनीतिक क्षेत्रों में सही सन्देह व्यक्त किया गया कि मारा काण्ड ब्रिटेन की गुप्त सहानुभूति के कारण ही सम्भव हो सका था और इसलिए ब्रिटिश सरकार में विद्रोह को दबाने के लिए कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की।

ब्रिटिश गवर्नर ने स्मिथ सरकार को पदच्युत कर दिया और ब्रिटेन ने दक्षिणी रोडेशिया से अपने कूटनीतिक सम्बन्ध भग कर दिए तथा आर्थिक प्रतिबन्ध भी लगाए। नवम्बर 1965 में समुक्त राष्ट्रसघ की महासभा के प्रस्ताव में स्मिथ सरकार के कार्य की निन्दा की गयी और सदस्य राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे उसे न तो मान्यता दें और न ही उसके साथ व्यापार करें। आर्थिक प्रतिबन्धों और कूटनीतिक उपायों का स्मिथ सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। मई 1968 में सुरक्षा परिषद ने दक्षिणी रोडेशिया के विरुद्ध पूर्ण आर्थिक नाकेबन्दी का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका क्योंकि गुप्त रूप से स्मिथ सरकार को सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त होती रही।

नवम्बर 1969 में दक्षिण रोडेशिया की समद ने (जिस पर गोरों का प्रभाव छाया हुआ था) इयान स्मिथ सरकार का गौरा शासन स्थायी बना देने की व्यवस्था कर दी। ब्रिटेन और स्मिथ सरकार के बीच बातचीत के अनेक दौर चले किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। नवम्बर 1971 में ब्रिटिश विदेश मन्त्री डगलस ह्यूम और रोडेशियाई प्रधानमन्त्री स्मिथ के बीच एक समझौता हुआ जिसके द्वारा अफ्रीकी जनता के हितों पर भारी कुठाराघात किया गया। इस समझौते से स्मिथ सरकार के बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अफ्रीकी बहुमत का शासन स्थापित करने का उल्लेख समझौते में किया गया, लेकिन इस बारे में कोई निश्चित निधि निश्चित नहीं की गयी और भी अनेक ऐसे निर्णय लिए गए जो स्मिथ सरकार के पक्ष में थे। ब्रिटिश कंपनियों की रोडेशिया के साथ व्यापार करने की छूट दे दी

गयी ताकि आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण पिछले वर्षों का पाटा पूरा हो सके। समझौते पर जनमत जानने के लिए 'पियर्स आयोग' गठित किया गया। यही आशा की गयी थी कि पियर्स आयोग ऐसी रिपोर्ट देगा जो कि समझौते के लागू होने के पक्ष में होगी, लेकिन जब 207 पृष्ठों की रिपोर्ट में यह कहा गया कि रोडेशिया के बहुसंख्यक अफ्रीकी समझौते प्रस्ताव से असहमत हैं और दूसरा समर्थन रोडेशिया के केवल लगभग ढाई लाख गोरे लोगो ने ही किया है, तो मामला बिगड़ गया। इयान स्मिथ ने तुरन्त ही पियर्स रिपोर्ट को गैर-कानूनी ठहरा दिया और घोषणा कर दी कि नवम्बर 1971 के समझौते के आधार पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती।

दक्षिण रोडेशिया के अफ्रीकी राष्ट्रवादियों का असन्तोष बढ़ता गया और उग्रवादी तत्व संपर्प के लिए उतारू हो गए, छापामार युद्ध शुरू हो गया। 29 अप्रैल से 6 मई 1975 तक जमैका को राजधानी किंग्सटन में 33 देशों के नेताओं का राष्ट्रकुल सम्मेलन हुआ। अफ्रीकी देशों ने दक्षिण अफ्रीकी वस्तियों और रोडेशिया से गोरानाही समाप्त करने की जो आवाज उठाई उसकी गूँज सारे सम्मेलन में सुनाई दी। किंग्सटन के राष्ट्रकुल-सम्मेलन के निर्णय के बाद रोडेशिया में घटना-क्रम बहुत तेजी से बदला। रोडेशिया के राष्ट्रवादी नेता जोसुआ मोकोमो ने आरोप लगाया कि इयान स्मिथ की सरकार शान्तिपूर्वक अफ्रीकियों को सत्ता सौंपना नहीं चाहती। बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और उग्र नवम्बर, 1975 में संयुक्तराष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव से रोडेशिया के राष्ट्रवादियों के हाथ मजबूत हो गए कि बहुमत अफ्रीकी शासन का सिद्धान्त मान लेने पर ही रोडेशिया की स्वतन्त्रता के लिए बातचीत होनी चाहिए। महासभा ने ब्रिटेन से यह अनुरोध किया कि रोडेशिया में इयान स्मिथ की गैर-कानूनी सरकार को किसी भी हालत में और कभी भी ब्रिटेन से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। महासभा ने अफ्रीकी जनता की स्वाधीनता की माँग का पूर्ण समर्थन किया और अफ्रीकी राष्ट्रीय परिषद् से कहा कि वह स्वाधीनता के लिए अपना आन्दोलन जारी रखे।

रोडेशिया समस्या के समाधान में गतिरोध नाशम रहा। इयान स्मिथ ने अगस्त, 1977 के चुनावों में अपने हथकण्डों से भारी विजय प्राप्त की। वर्ष 1979 के शुरू में रोडेशिया समस्या समाधान के लिए जो प्रयास शुरू किए गए, उनके फलस्वरूप देश को एक नए संविधान का प्राख्य दिया गया। प्राख्य के पहले अध्याय में यह कहा गया कि देश का नाम 'जिवाब्वे-रोडेशिया' होगा। उसके बाद के अध्यायों में सम्मर्प के गठन, न्यायपालिका, सुरक्षा सेनाओं सम्बन्धी आर्थिक न्यायिक सेवाओं की भूमिका आदि का उल्लेख किया गया। कहा गया कि संसद के दो सदन होंगे—सीनेट और विधानसभा। संसद का कार्यकाल पाँच साल होगा। राष्ट्रीय सरकार का काम मन्त्रियों की कार्यपालिका चलाएगी। प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसके दल को विधानसभा में अधिक स्थान प्राप्त होंगे। 10 सितम्बर, 1979 को रोडेशिया पर लन्दन में सांविधानिक सम्मेलन शुरू हुआ और 21 सितम्बर, 1979 को जिवाब्वे-रोडेशिया द्वारा सम्मेलन में ब्रिटिश प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश योजना यह थी कि जिवाब्वे में अफ्रीकी बहुसंख्यकों की सरकार की

स्थापना हो जाएगी। गोरों का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। 27 अक्टूबर, 1979 को रोडेशिया के प्रधानमंत्री मुजोरेवा द्वारा लन्दन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 15 नवम्बर, 1979 को देशभक्त मोर्चे द्वारा रोडेशिया पर ब्रिटिश प्रारूप स्वीकार किया गया। 5 दिसम्बर, 1979 को लन्दन में रोडेशिया-समझौते की घोषणा की गई। 12 दिसम्बर, 1979 को रोडेशिया के विरुद्ध ब्रिटिश आर्थिक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए गए। 22 दिसम्बर, 1979 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोडेशिया के विरुद्ध 14 वर्षीय प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया।

रोडेशिया का स्वाधीन होना (स्वाधीन जिबाब्वे)

14 मार्च, 1980 को ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड सोमेश द्वारा घोषणा की गई कि 18 अप्रैल, 1980 को रोडेशिया को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कर दी जायगी। अखिर 17-18 अप्रैल, 1980 को मध्यरात्रि को जिबाब्वे (रोडेशिया) को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो गई। ब्रितानी यूनियन जैक के स्थान पर जिबाब्वे के पाँच रंगों (लाल, सुनहरी, हरा, काला और सफेद) का ध्वज फहराया गया। नवस्वाधीन जिबाब्वे के समक्ष कई तरह की समस्याएँ हैं। इस समय सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गोरों का भी प्रभाव है। बहुराष्ट्रीय निगमों भी वहाँ पर काफी मस्या में हैं और निजी पूँजी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगी हुई है।

अरब राज्य संघ : बिखराव की ओर

1945 में अस्तित्व में आए अरब राज्य सघ में एकता का सदैव से ही अभाव रहा है और 1981 के अन्तिम चरण में इसके सदस्यों में आपसी फूट जिस तेजी से उभर कर सामने आई उससे इसके बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। 26 नवम्बर, 1981 को फेज (मोरक्को) में 20-सदस्यीय अरब राज्य संघ का सम्मेलन शुरू तो हुआ लेकिन पाँच घण्टे की बहस के बाद ही शाह हुसैन द्वितीय ने उसे स्थगित कर दिया और गुस्ते में विदेश मन्त्रियों ने केवल इतना ही कहा कि वे परस्पर वार्ता द्वारा अगले शिखर सम्मेलन की तारीख तय करें।

इस शिखर सम्मेलन में सद्भावना का जितना अभाव था उतना शायद अम्मान और बगदाद में हुए (1979 और 1980) शिखर सम्मेलनों में भी नहीं रहा होगा। लीबिया, अल्जीरिया, सीरिया, ईराक और मारितानिया के राज्याध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उनका प्रतिनिधित्व उनके विदेश मन्त्रियों ने किया। उनकी अनुपस्थिति का कारण पश्चिमेशिया में शान्ति स्थापित करने के लिए सऊदी अरब का प्रस्ताव था। लीबिया के विदेश मन्त्री अब्दुलादी घोबेदी ने इस शान्ति प्रस्ताव को 'गद्दार प्रस्ताव' करार दिया।

इस तरह की शब्दावली का उपयोग अरब राज्य सघ के मंच से पहले भी हो चुका है। जब कंप डेविड में मिस्त्र और इजरायल में शान्ति स्थापना सम्बन्धी सन्धि हुई थी, तब मिस्त्र के लिए 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल हुआ था। अपना विरोध व्यक्त करने के लिए मिस्त्र ने अपना राजदूत बुलाने की पहल सऊदी अरब ने की थी। अभी अरब राज्य संघ के संस्थापक सदस्यों में से माना जाने वाला मिस्त्र घबरा

समूह का सदस्य नहीं है। काहिरा के बाद अरब राज्य संघ के मुख्यालय के प्रश्न को लेकर जिस तरह का तनाव पैदा हो गया था उसी दिन से इस संगठन के बिलराज की प्रक्रिया शुरू हुई और तब से आरम्भ विघटन की इस प्रक्रिया पर विराम नहीं लगा है।

मिस्र जब अरब राज्य संघ से अलग हुआ तब भी उसके पीछे अमेरिका था, मिस्र और इजरायल में कंग डेविड समझौता कराने में अहम भूमिका अदा करने वाला। प्रेक्षकों के अनुसार सऊदी अरब के पश्चिमेशिया शान्ति प्रस्ताव में भी अमेरिकी भूमिका की गंध आती है, यद्यपि इस समझौते में इजरायल को मान्यता देने की धारा है और साथ ही स्वाधीन फिलिस्तीन की स्थापना का भी उल्लेख है। यही उल्लेख इजरायल के गले नहीं उतर पा रहा है। इजरायल को सऊदी अरब का प्रस्ताव शायद इनीचिए नागवार गुजरा है। मसला फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे का समाधान ढूँढना ही है जिस पर कंग डेविड समझौते में भी उल्लेख था। यदि दोनों बड़े देश 'ईमानदारी' के साथ इस समस्या का हल ढूँढ़ें तो यह असम्भव नहीं है लेकिन घटकाब परस्पर स्वाधों और हितों को लेकर पैदा हो जाता है।

अरब देशों की अपनी-अपनी पसन्दगी और नापसन्दगी का यह असर तो हुआ ही है कि इस बड़े संगठन के बीच में छोटे-छोटे संगठन अस्तित्व में आने लगे हैं। उन्हें डर है कि यदि छोटे देश मिलकर नहीं रहेंगे तो आधुनिक शस्त्रों से लैस बड़े देश उन्हें 'कब्जिया' सकते हैं। एक बार बक्का हो जाने के बाद के हथ से वे भली-भाँति परिचित हैं।

लिहाजा खाड़ी के पाँच देशों ने अपना एक अलग संगठन बनाया है। इस संगठन की सामान्य आर्थिक और सैनिक नीतियाँ होंगी। उन्होंने अपनी सामान्य नौसैनिक शक्ति भी गठित करने का फैसला किया है।

22 मार्च, 1945 को अरब राज्य संघ औपचारिक तौर पर अस्तित्व में आया। इसके संस्थापक सदस्यों में मिस्र, ईराक, जोर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन थे। बाद में प्रल्जीरिया, बहरीन, जिबूती, कुवैत, लीबिया, मारितानिया, मोरक्को, रोमान, बतार, सोमालिया, सूडान, ट्यूनिशिया संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण यमन शामिल हो गए। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे को पूर्ण सदस्य के रूप में इस संगठन में शामिल किया गया। मार्च, 1979 में मिस्र द्वारा इजरायल के साथ शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर करने के कारण मिस्र को अरब राज्य संघ की सदस्यता से निलम्बित कर दिया गया। इसका मुख्यालय भी काहिरा से बदल कर ट्यूनीशिया कर दिया गया।

बेशक 1945 में अरब राज्य संघ की विधिवत स्थापना हुई थी लेकिन 13 दिसम्बर, 1931 को यरुशलम में एक गैरसरकारी राष्ट्रीय अरब कांग्रेस ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि अरब देशों की एकता और स्वतन्त्रता हर तरह से प्राप्ति की जाएगी। 25 सितम्बर, 1944 को बिरुन्दरिया में अरब सम्मेलन

की तैयारी सभा का उद्घाटन हुआ जिसमें अक्टूबर, 1944 तक आठ बैठकें आयोजित हुईं। इसमें अरब राज्य सभ के उद्देश्य और उसके सिद्धान्तों का फैसला किया गया। ये सिद्धान्त मोटे तौर पर इस प्रकार थे—सभी सदस्य राज्यों की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता का आदर, प्रत्येक राज्य की शासन प्रणाली का सम्मान, आक्रमण से परहेज करना और भगड़ो को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाना, विदेश नीति और अन्य देशों से सम्झौते करने के अधिकार में सदस्य देशों को स्वाधीनता, सदस्य राज्यों के बीच सम्बन्ध दृढ़ करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य के विशेष स्थान और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सदस्य राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की स्थापना।

अरब राज्य सभ का काम करने के लिए एक परिषद्, एक महासचिव और कुछ स्थायी समितियों की व्यवस्था की गई। अरब राज्य सभ के कुछ विशिष्ट अभिकरण इस प्रकार हैं—अरब शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सगठन, अरब राज्यों का प्रसारण सभ, अरब श्रम-सगठन, अरब राज्यों का नागरिक विमानचालन परिषद्, आर्थिक परिषद्, अरब नगर सगठन, संयुक्त सुरक्षा परिषद्, सामाजिक रक्षा के लिए। संगठन आदि संयुक्त राष्ट्र की तरह अरब राज्य सभ का ही एक मुख्यालय भी है जब तक मिस्र इस सगठन का सदस्य रहा अरब राज्य सभ का कार्य मोटे तौर पर सामान्य ढंग से चलता रहा लेकिन उसकी मुअत्तती के बाद परस्पर सशय का वातावरण जो बना तो उसमें कहीं भी सद्भावना के पुट देखने को नहीं मिले।

लेटिन अमेरिका का जागरण (Resurgence of Latin America)

लेटिन-अमेरिका में अभिप्राय

‘लेटिन अमेरिका’ शब्दावली से उन 24 गणतन्त्रों का बोध होता है जो उत्तर में संयुक्तराज्य अमेरिका, मैक्सिको के सीमान्तों और मैक्सिको की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ड्रेक पैसेज (Drake Passage) तथा अन्टार्कटिक महासागर के बाहरी भाग तक स्थित है। लेटिन अमेरिका को प्रायः तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है, यथा—पहला, मध्य अमेरिका जिसमें सात गणतन्त्र हैं, दूसरा, केरीबियन जिसमें तीन गणतन्त्र हैं और तीसरा, दक्षिणी अमेरिका जिसमें दस गणतन्त्र हैं। लेटिन अमेरिका के ये बीस राज्य लगभग 80 लाख वर्गमील क्षेत्र घेरे हुए हैं और इनकी कुल जनसंख्या 30 करोड़ के लगभग है। द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में जनसंख्या, जागरण और प्रगति नीचे दृष्टियों से लेटिन अमेरिका ने काफी प्रगति की है। पश्चिमी गोलार्ध के इन सभी राष्ट्रों में लेटिन संस्कृति की ममान पृष्ठभूमि है। वास्तव-शक्तियों द्वारा प्रणामित द्वीपों को लेटिन अमेरिका की परिधि में समाहित नहीं किया जाता। लेटिन अमेरिका को केवल दक्षिणी अमेरिका कहना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि द्रुवीय सीमाएँ केवल दक्षिण तक मर्यादित न रहकर उत्तर में भी प्रवेश कर जाती हैं। इस सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि का क्षेत्रफल, तुलनात्मक रूप से, संयुक्तराज्य

अमेरिका से लगभग तिगुना है तथा अफ्रीका का तीन-चौथाई है। यहाँ रहने वालों में भारतीय, स्पेनिश, पुर्तगाली, इटालियन तथा जापानी लोग भी हैं।

लेटिन अमेरिका का स्वाधीन होना

लेटिन अमेरिका के राज्यों ने भी उसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त की है जिस प्रकार संयुक्तराज्य अमेरिका को प्राप्त हुई थी। स्वाधीन होने से पूर्व लेटिन अमेरिका में फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन के उपनिवेश कायम थे। लम्बे संघर्ष के बाद दक्षिण अमेरिका के पुर्तगाली भाषा-भाषी लोगों को स्वाधीनता प्राप्त हुई और सीमाव्यवस्था इन्होंने स्वतन्त्रता के बाद भी अपनी एकता कायम रखी। फलस्वरूप इनका जो स्वाधीन राज्य सन् 1825 में स्थापित हुआ वह ब्राजील के सघीय राज्य के नाम से हमारे सामने है। दूसरी ओर स्पेन के उपनिवेशों में अपना समारम्भ घाठ भिन्न राष्ट्रों के रूप में किया। ये राष्ट्र थे—मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कोलम्बिया, पेरू, बोलीविया, पैरागुए, अर्जेन्टाइना और चिली किन्तु लगभग एक शताब्दी में ही इन घाठ राज्यों ने मठारह राष्ट्रों का रूप ले लिया। सन् 1828 में उरुग्वे ने अर्जेन्टाइना के विरुद्ध विद्रोह किया और सन् 1830 में वह एक स्वतन्त्र राज्य बन गया। इसी तरह कोलम्बिया का सन् 1830 में तीन राज्यों में विभाजन हो गया—वेनेजुएला, कोलम्बिया और इक्वेडोर। सन् 1844 में डॉमिनिकन गणराज्य ने स्वतन्त्रता प्राप्त करली और सन् 1898 में क्यूबा भी स्पेन के झिज्जे से निकलकर स्वतन्त्र हो गया। पनामा ने कोलम्बिया से पृथक् होकर सन् 1903 में पृथक् राज्य का रूप ग्रहण किया। इन विद्रोहों के फलस्वरूप लेटिन अमेरिकी राज्यों की वह भूमिका, जो स्पेनिश और पुर्तगाली साम्राज्यों से उदय हुई थी, नई दुनिया में परिणत हो गई। सन् 1840 में मध्य अमेरिका के पाँच राज्य बन गए—ग्वाटेमाला, होन्डुरास, निकारागुआ, एल साल्वेडोर तथा कोस्टारिका। सन् 1821 में संघटो डॉमिनियो स्पेनिश नियन्त्रण से मुक्ति पा चुका था। लम्बे संघर्ष के बाद सन् 1898 में क्यूबा ने स्पेन से स्वतन्त्रता प्राप्त कर पृथक् राज्य का गौरव हाँसिल किया। वर्तमान में कुल मिलाकर 24 लेटिन अमेरिकी गणराज्य हैं जिनके नाम ये हैं¹—

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. अर्जेन्टाइना (Argentina) | 2. उरुग्वे (Uruguay) |
| 3. क्यूबा (Cuba) | 4. ब्राजील (Brazil) |
| 5. कोस्टारिका (Costarica) | 6. पैरागुए (Paraguay) |
| 7. एल साल्वेडोर (El Salvador) | 8. होन्डुरास (Honduras) |
| 9. मैक्सिको (Mexico) | 10. निकारागुआ (Nicaragua) |
| 11. वेनेजुएला (Venezuela) | 12. चिली (Chile) |
| 13. पनामा (Panama) | 14. कोलम्बिया (Colombia) |
| 15. इक्वेडोर (Equador) | 16. बोलीविया (Bolivia) |
| 17. ग्वाटेमाला (Guatemala) | 18. पेरू (Peru) |

- | | |
|---|-------------------------------|
| 19. नीग्रो गणराज्य-हेटी
(Negroid-Haiti) | 20. बार्बाडोस (Barbados) |
| 21. डोमिनिकन गणराज्य
(Dominican Republic) | 22. जमैका (Jamaica) |
| 23. ट्रिनिडाड तथा टोबैगो
(Trinidad and Tobago) | 24. गायना (East India-Guiana) |

लेटिन अमेरिका के सभी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील सबसे विशाल है, यहाँ के पन्ने की खानें विश्व प्रसिद्ध हैं और साथ ही यह विश्व का सबसे अधिक कॉफी-उत्पादक देश है।

20वीं सदी में लेटिन अमेरिका की मौलिक समस्याएँ, प्रभाव व जागरण

ऐतिहासिक विभिन्नताओं ने एंग्लो-सेक्शन अमेरिका और लेटिन अमेरिका को दो भिन्न समाजों का रूप दिया है जिनकी प्रकृति और महत्व, उद्देश्य और आदर्श अलग-अलग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने अपने लेटिन अमेरिकी पड़ोसियों की समस्याओं और प्राथमिकताओं की अवहेलना करके अपना विकास जारी रखा है।¹ इस अवहेलना के 19वीं शताब्दी में तो विशेष दुष्परिणाम नहीं निकले, किन्तु बीसवीं शताब्दी से, जबकि विश्व के सभी भाग एक दूसरे पर तेजी से अन्तर्निर्भर होते जा रहे हैं, इन दो अमेरिकाओं के बीच सहानुभूतिपूर्ण सहभावना की कमी के गम्भीर परिणाम निकले और कुछ परिणाम तो द्वितीय महायुद्ध के बाद कठोर संघर्षों के रूप में परिणत हो गए।²

बीसवीं शताब्दी में लेटिन अमेरिका को कुछ मौलिक समस्याओं से जूझना पड़ा है जिसका न केवल लेटिन अमेरिका की आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों पर बल्कि काफी सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रवाह पर भी प्रभाव पड़ा है। ब्रून एव मैमले ने इन समस्याओं और प्रभावों का विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है जिसका संक्षेप, उन्हीं के शब्दों में, निम्नानुसार है³—

“लेटिन अमेरिका के लोगों ने 20वीं शताब्दी में जिन कठिनाइयों का सामना किया उनमें तीन अनिश्चित समस्याओं ने और भी वृद्धि कर दी। पहली समस्या थी लेटिन अमेरिका की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। दूसरी समस्या आर्थिक थी। साधनों का सर्वोत्तम विकास किस प्रकार किया जाए ताकि बढ़ते हुए लाखों लोगों की आय में वृद्धि करके सामान्य जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया जा सके? तीसरी समस्या प्रशासकीय थी—किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था तथा किस प्रकार की सरकार हो जो आज के इस प्रतियोगितापूर्ण विश्व में इस निर्धन और सघर्षरत जनता का अस्तित्व कायम रख उनके बल्याण में वृद्धि कर सके। ये तीनों समस्याएँ

नई नहीं थी। साधन, सुरक्षा और सामाजिक न्याय की समस्या को कोई भी राष्ट्र या सरकार ज्यादा समय तक टाल नहीं सकती थी। फिर भी 20वीं शताब्दी के मध्य में जिस गति से लेटिन अमेरिका की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, इससे कुशल सरकार और साधनों के समुचित प्रयोग को तुरन्त आवश्यक बना दिया।"

"जनसंख्या के दबाव और सीमित आय दोनों ने सरकार के लिए यह आवश्यक बना दिया कि पूर्ण संकेंद्रता और कुशलता के साथ अर्थ-व्यवस्था को विकसित किया जाए। किन्तु यह कौन-सी कुशल प्रशासन व्यवस्था हो सकती थी? विश्व के अधीर देश, जो प्रति व्यक्ति अधिक आर्थिक आय का उपभोग कर रहे थे वे जनतन्त्र के प्रतिपादक थे लेकिन कुछ देशों में जो अपने साधनों का विकास कर रहे थे और अपनी अर्थ-व्यवस्था को उन्नत बना रहे थे, साम्यवादी शासन था। क्या साम्यवाद आर्थिक समृद्धि को तेजी से बढ़ा सकता था और जनतन्त्र की अपेक्षा अधिक न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था कर सकता था? विश्व की निर्धन जनता के सामने यह एक प्रश्न-चिह्न था और विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या निर्धन थी। यही प्रश्न लेटिन अमेरिकी जनता के सम्मुख था।"

"जनतन्त्र को जिस रूप में आंग्ल-मेक्सन और अमेरिका की जनता ने समझा था, उसने लेटिन अमेरिका की मतह कोकभी छुपा भी नहीं था। सम्पूर्ण उपनिवेशवादी काल में सत्ता का प्रयोग सुदूर-स्थित राजा द्वारा किया जाता था, राजा जो बैट्रिड में (या ब्राजील के लिए तिस्वन में) या बैबी अक्विटारो के आधार पर शासन करता था। आजादी की डेढ़ शताब्दी बाद भी लेटिन अमेरिका के लोगों में जनतन्त्रीय परम्पराओं का अभाव था। उनके बुद्धिवादी नेताओं ने, जिन्होंने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की जनतन्त्र प्रणाली का अध्ययन किया था, आदर्श संविधानों का निर्माण किया, लेकिन जन-समूह सरकार के आदर्श-कानूनों को न तो पढ़ सकता था और न समझ सकता था। उनके लिए नेता ही सत्ता का प्रतीक था—ऐसा शासन (Caudillo) जिसकी आज्ञा का पालन किया जाता था क्योंकि उसके पाम आज्ञा-पालन करना सक्ने की शक्ति थी। जनमत पर आधारित सत्ता द्वारा राष्ट्रपति शासन करे, यह सिद्धान्त उनको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सका क्योंकि यह वास्तविकता को झुठलाता था। उन्होंने यही देखा था कि निर्वाचित राष्ट्रपति को कोई भी नेता एक सकल सैनिक क्रान्ति द्वारा हटाकर सत्ता उस समय तक के लिए छीन लेता था जब तक कि कोई और नेता हिंसा के प्रयोग द्वारा उसका स्थान न ले ले। यह पिछार हमेशा प्रबल रहा है कि सत्ता उसी व्यक्ति या दल में निवास करती है जिसमें सत्ता पाने की इच्छा और शक्ति होती है क्योंकि राजनीतिक वास्तविकताओं ने हमेशा इसी का समर्थन किया था।"

"लेटिन अमेरिका एक शक्तिशाली व्यक्ति या तानाशाह से ही, जो पुलिस और सैन्य पर नियन्त्रण रख कर किसी भी विरोधी दल को पनपने नहीं दे, परिचित था। पूर्ण सत्ताधारी तानाशाह ही परिचित राजनीतिक आदर्श था। इस प्रकार की विचारधारा और व्यवहार की निरन्तरता के कारण जनतन्त्र और उत्तरदायी सरकार

के आधारभूत सिद्धान्तों, विभाजित सत्ता, अवरोध, सन्तुलन तथा सीमाओं के स्थान पर लेटिन अमेरिका के बहुत-से निवासियों ने साम्यवादी शासन के तानाशाही तरीकों को अधिक उपयुक्त समझा। उन लोगों से, जो तानाशाह को ही सरकार और कानून समझते थे, यह बहस करना निरर्थक था कि एक संविधान, सामाजिक स्वतन्त्रता का अधिकार, भाषण की स्वतन्त्रता स्वतन्त्र चुनाव आदि जनतन्त्र ही प्रदान करता है। निश्चित परम्पराएँ, सोचने के तरीके और सत्ता के व्यवस्थित परिवर्तन की कानूनी परम्पराएँ लेटिन अमेरिका में न तो विकसित ही हो सकी और न स्थिति की जा सकी। जनतन्त्र के इन उदार और दृढ़ आधारों की कमी ने फासिस्ट, नात्सी और साम्यवाद जैसी तानाशाही विचारधाराओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।”

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका के विचारों एवं राजनीतिक संस्थाओं से इन राज्यों ने प्रेरणा एवं मार्गदर्शन ग्रहण किया किन्तु यहाँ के राजनीतिक विचारकों की यह गलती रही कि इन्होंने उत्तरी-अमेरिका के निश्चित संविधान, सरकार के गणतन्त्रात्मक स्वरूप, आदि संस्थाओं के सफल संचालन को तो देखा और यह आशा भी की कि इनके अपनाते पर स्थिरता एवं सम्पन्नता प्राप्त की जा सकती है, किन्तु उन्होंने यह नहीं देखा कि क्या उनके देश में इन संस्थाओं को अपनाते योग्य अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि गृहयुद्ध छिड़ गया तथा अनेक लेटिन अमेरिकी राज्यों को रक्तपात, तानाशाही और गरीबी आदि अभिशापों का सामना करना पड़ा। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक ब्राजील, चिली, और अर्जेन्टाइना ही तीन ऐसे राज्य थे जहाँ राजनीतिक स्थिरता एवं प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं के विकास की आशा की जा सकती थी। बाद में कोलम्बिया कोस्टारिका, मैक्सिको, ऊरुग्वे आदि राज्य भी इसी श्रेणी में आ गए। अर्जेन्टाइना तथा ब्राजील में तानाशाही शासन स्थापित हो गया, किन्तु सन् 1956 में वहाँ पुनः प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं का उदय होने लगा। मैक्सिको में एकदलीय व्यवस्था के साथ विरोधीकृत प्रजातन्त्र (Qualified Democracy) को अपनाया गया। ऊरुग्वे को लेटिन अमेरिका का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा विकासशील प्रजातन्त्र देश माना जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लेटिन अमेरिका (Latin America in International Field)

संयुक्तराज्य अमेरिका और लेटिन अमेरिकी देश—सत्तार के अन्य राष्ट्रों में लेटिन अमेरिका का सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध संयुक्तराज्य अमेरिका से है। यहाँ के राज्यों की दृष्टि से अमेरिका दुनिया की शक्तिशाली शक्ति और स्वतन्त्रता का प्रतीक था। तत्कालीन उपनिवेशवादी शक्तियों के लिए यह एक भारी खतरा था। लेटिन अमेरिका के राज्यों को उनके स्वतन्त्र घाटोलनों में संयुक्तराज्य अमेरिका ने दृढ़ समर्थन दिया था। लेकिन इस समर्थन के पीछे उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएँ गतिहित थी और इसीलिए अमेरिका की लेटिन अमेरिकी नीति को ‘यॉंकी साम्राज्यवाद’ (Yanki Imperialism) और डॉलर दूतनीति (Dollar Diplomacy) का नाम

दिया जाता है। इस नीति के विकास की विभिन्न मजिलें रही हैं और हर मंजिल पर इस नीति को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता रहा है।

पहली मंजिल 19वीं सदी में 'मुनरो-सिद्धान्त' के रूप में दृष्टिगोचर होती है जिसका प्रतिपादन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो द्वारा दक्षिण में यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आक्रामक खेदों की पृष्ठभूमि में किया गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लेटिन अमेरिकी राज्यों को मान्यता प्रदान करने वाला सर्वप्रथम देश संयुक्त-राज्य अमेरिका ही था और सन् 1823 में मुनरो सिद्धान्त द्वारा अमेरिका ने नई दुनिया में उपनिवेश स्थापित करने के विरुद्ध चेतावनी दे दी और स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी राज्यों के मामले में किसी दूसरे के हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जाएगा। लेटिन अमेरिकी राज्यों में इस सिद्धान्त की मनुकुल प्रतिक्रिया हुई। उस समय ये देश इस बात को नहीं माँप सके कि मुनरो-सिद्धान्त का सहारा लेकर संयुक्तराज्य अमेरिका उन पर अपने अनियन्त्रित राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने का खेल खेल रहा है। इसके उपरान्त दूसरी मंजिल आई जिसे विल्यम डी हवेल्ल द्वारा प्रतिपादित 'बड़ी डण्डा-नीति' (Big Stick Policy) कहा जाता है। तीसरी मंजिल की नीति 'डॉक्टर कूटनीति' कहलाती है जिनकी रचना विलियम टाफ्ट ने की थी। इन सभी मंजिलों के दौरान, संयुक्तराज्य अमेरिका लेटिन अमेरिकी राज्यों में अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करता रहा और औद्योगिक रूप से निरक्षर रहते हुए भी उसने इन राज्यों के सबसे प्रमुख बाहरी मित्र की भूमिका बढ़ा दी। सन् 1904 में अमेरिका ने पनामा के साथ हे बुनाऊ-वरेला (Hay-Bunau-Verilla) की सन्धि की जिसके अनुसार नहर की रक्षा के लिए वह इस राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। इस प्रकार संरक्षित राज्यों (Protectorates) का समय प्रारम्भ हुआ। डोमिनिकन गणराज्यों को सन् 1905 से 1924 तक अधिकार में रखा गया। निकारगुआ, हैटी आदि पर अमेरिका का संरक्षण स्थापित रहा। क्यूबा ने अमेरिका सहयोग से स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, अतः उसे भी स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने के की अनुमति नहीं दी गई। इन चार राज्यों पर अमेरिकी सैनिक प्रभाव रहा। बुडरो विल्सन के समय अमेरिकी भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ, संरक्षित अमेरिकी साम्राज्यवाद का पतन होने लगा और अच्छे पड़ोसी-सम्बन्धों की सृष्टि हुई। चौथी मंजिल में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की 'अच्छे पड़ोसी की नीति' का नमूना आता है। उनके राष्ट्रपतित्व काल में लेटिन अमेरिका के राज्य हैटी पर से अमेरिका का अन्तिम प्रभाव भी हटा लिया गया और दोनों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का सूत्रपात हुआ। रूजवेल्ट के शासन काल में पश्चिमी गोलार्द्ध की सुरक्षा, सम्पन्नता एवं सद्भावना की दृष्टि से अनेक कार्य किए गए। भ्रातृत्व के भाव विकसित करने के लिए अमेरिका में अनेक सम्मेलन हुए। पाँचवीं मंजिल की नीति का निर्माण ब्राइजनहावर ने किया जिसे 'अच्छे सामीदार' (Good Partner) की नीति कहा जाता है। ब्राइजनहावर-प्रशासन ने लेटिन अमेरिका के राज्यों को काफी तकनीकी सहयोग प्रदान किया। छठी मंजिल में कनेडी ने लेटिन अमेरिकी देशों के प्रति एक नवीन नीति प्रस्थापित

की जिसे 'प्रगति के लिए मंत्री' (Alliance for Progress) का नाम दिया गया। कॅनेडी-प्रशासन यह मानकर चला कि लेटिन अमेरिकी राज्यों में साम्यवाद का प्रसार स्वयं अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक धुनौती बन जाएगा। इसी आधार पर राष्ट्रपति कॅनेडी द्वारा क्यूबा के प्रश्न पर दृढ़ निर्णय लिया गया। क्यूबा में साम्यवादी सैनिक चौकियों की स्थापना अमेरिका के हितों एवं सुरक्षा पर एक गहरा आघात था। इसका विरोध करने के लिए अणु-अस्त्रों के प्रयोग तक की नौबत आ गई। सातवीं और अन्तिम मंजिल की रचना सन् 1969 में राष्ट्रपति निक्सन ने की और इस नीति को 'समान साझेदारी' (Equal Partnership) की नीति की संज्ञा दी गई। फोर्ड-प्रशासन ने निक्सन-नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। कार्टर के समय भी लेटिन अमेरिका के प्रति अमेरिकी-नीति लगभग पूर्ववत् बनी रही किन्तु उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति रीगन लेटिन अमेरिका में अधिकाधिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहे हैं। सन् 1981 में एलसाल्वाडोर के गृहयुद्ध में अमेरिका की जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी इसका स्पष्ट उदाहरण है। वास्तव में कुछ लेटिन अमेरिकी देशों की राजनीतिक अस्थिरता अमेरिका को हस्तक्षेप के लिए आमन्त्रित करती रहती है।

लेटिन अमेरिकी राज्यों के प्रति संयुक्तराज्य अमेरिका की नीतियों को चाहे जिस नाम से पुकारा गया, इस मत को ठुकराना कठिन है कि नीतियों का स्वरूप हमेशा किसी न किसी रूप में साम्राज्यवादी रहा है। इन नीतियों के माध्यम से अमेरिका ने लेटिन अमेरिकी क्षेत्र में अपने प्रभाव में अभिवृद्धि की वहीं अपनी कठपुतली सरकारें कायम की, लेटिन अमेरिकी राज्यों के आन्तरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप कर उनकी सम्प्रभुता की अवहेलना की गई और कई अवसरों पर ऐसे युद्धों को जन्म दिया, जिन्हें नैतिक दृष्टि से कभी उचित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में अमेरिका ने लेटिन अमेरिकी राज्यों को एक प्रकार से अपनी जमींदारी समझा है, डॉनर फैक कर या सैनिक हस्तक्षेप करके उन्हें अपने शिकरों में जकड़े रखने की नीति अपनाई गई है। लेकिन क्यूबा जैसे राज्य अमेरिकी प्रभाव-क्षेत्र से मुक्त होकर अपनी सम्प्रभुता का झण्डा फहरा रहे हैं और इसमें सन्देह नहीं कि निकट भविष्य में लेटिन अमेरिका में संयुक्तराज्य अमेरिका के 'साम्राज्यवाद' का अन्त होकर रहेगा। लेटिन अमेरिका में लोकतान्त्रिक गतिविधियाँ प्रबल होती जा रही हैं और उन प्रतिगामी सरकारों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है जिनका अस्तित्व संयुक्तराज्य अमेरिका की सहायता पर निर्भर है।

यूरोप के देश और लेटिन अमेरिका—जहाँ तक लेटिन अमेरिका के राज्यों तथा यूरोप के देशों से इनके सम्बन्धों का प्रश्न है, यह बहा जाता है कि प्रारम्भ से ही यूरोप के देशों ने यहाँ उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। इन राज्यों ने स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के बाद यूरोप की शक्ति-राजनीति में बहुत कम भाग लिया, किन्तु विगत दोनो ही महायुद्धों में इनका सन्निध सहयोग रहा। यहाँ के अधिकांश राज्यों पर स्पेन की सत्कृति का स्पष्ट प्रभाव है, अतः स्वतन्त्रता के बाद स्पेन के साथ इनके सम्बन्ध घनिष्ठ हो गए। स्पेन में फ्रांसी-शामन के प्रति लेटिन अमेरिका के राज्यों में

मतभेद था, इनसे ये सम्बन्ध कुछ कमजोर पड़े। ब्राजील तथा पुर्तगाल से इनके सम्बन्ध सदा ही मित्रतापूर्ण रहे हैं। फ्रांस के साथ यहाँ के राज्यों के प्रारम्भ से ही अच्छे सम्बन्ध नहीं रहे हैं, किन्तु यहाँ फ्रांस की सत्कृति का प्रभाव बहुत अधिक है। यहाँ की भाषा, साहित्य, कला, फैशन, पहनावे आदि पर फ्रांस का स्पष्ट प्रभाव है। जर्मनी के साथ लेटिन अमेरिका के सम्बन्ध प्रायः आर्थिक रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लेटिन अमेरिका के महत्त्व में अभिवृद्धि : सम्भावनाएँ व बाधाएँ

निकट भविष्य में लेटिन अमेरिका के राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्व बढ़ जाएगा। इस सम्भावना के अनेक कारण हैं जिनमें से मुख्य निम्नांकित हैं—

- (1) इस क्षेत्र की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही है।
- (2) यहाँ कच्चे माल का सबसे अधिक उत्पादन होता है।
- (3) यह अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) का एक बड़ा भाग है।
- (4) इस प्रदेश के राज्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं वे अत्यन्त फुलल तथा तीव्र बुद्धि के राजनीतिज्ञ होते हैं।
- (5) ये राज्य संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिकी राज्यों के संगठन तथा अमेरिका के सहयोग से औद्योगीकरण एवं नवीनीकरण करने में सलग्न हैं।

लेटिन अमेरिका की प्रगति में आशा के उक्त सकेतों के अतिरिक्त मार्ग की अनेक बाधाएँ भी हैं जो इस क्षेत्र के विकास की गति को धीमी बनाती हैं। ये बाधाएँ प्रश्लिष्टित हैं—

- (1) इन राज्यों की भौगोलिक बनावट के कारण एक-दूसरे के बीच आवागमन के साधन स्थापित करना तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध बढ़ाना मुश्किल है।
- (2) इस प्रदेश के अधिकांश राज्यों में बहुत समय से राजनीतिक अस्थिरता, अप्टाचार तथा अप्रजातान्त्रिक व्यवहारों का बोलबाला है।
- (3) इन राज्यों की अर्थ-व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के साथ मेल नहीं खाता। वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक विकास दोनों से युक्त अर्थ-व्यवस्था का इन राज्यों में अभाव है।

(4) इन राज्यों में लोगों की सामाजिक स्थिति बड़ी असन्तोषजनक है, अधिकांश लोग गरीबी तथा अशिक्षा के शिकार हैं। इसके अतिरिक्त रंगभेद की नीति के कारण व्यक्ति की समानता का सिद्धान्त भी क्रियान्वित नहीं हो पाता।

(5) रोगन केंथोलिक चर्च के महत्त्व के सम्बन्ध में इन देशों में भारी वाद-विवाद है। कुछ कहते हैं कि चर्च को राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किन्तु दूसरों का मत इसके विपरीत है। दक्षिण-अमेरिका में जब स्वतन्त्रता के लिए युद्ध किया गया था तो चर्च ने स्पेन का समर्थन किया था। यह बात अभी तक इन राज्यों को याद है फिर भी चर्च के समर्थक व धर्म के अनुयायी चर्च के समर्थक हैं।

(6) इन राज्यों पर समुक्तराज्य अमेरिका का भारी प्रभाव रहता है और जिसके कारण इस क्षेत्र के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते रहते हैं।

(7) इन राज्यों पर धीरे-धीरे साम्यवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इससे पूर्व यहाँ फासीवादी प्रवृत्तियों का जोर था, किन्तु साम्यवाद ने आसानी से उसका स्थान ग्रहण कर लिया क्योंकि—

(i) यहाँ फासीवाद प्रजातन्त्र का बाना पहने हुए है, (ii) यह एक जानि की सर्वोच्चता पर जोर नहीं देता, (iii) यह धर्म पर आधारित नहीं है। स्टुअर्ट का कहना है कि “लेटिन अमेरिकी गणतन्त्र में प्रजातन्त्र की अपेक्षा साम्यवाद अधिक प्रभावी है क्योंकि यहाँ विदेशी पूँजीपतियों अथवा राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों द्वारा जनता का शोषण एक सामान्य बात हो गई है।” लेटिन अमेरिका के साम्यवादी नेताओं पर सन् 1939 में कॉमिन्टर्न (Comintern) का प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो गया। ब्राजील, चिली (Chile), अर्जेंटीना, मैक्सिको, क्यूबा आदि राज्यों में साम्यवादी नेता शक्ति प्राप्त करने लगे। ग्वाटेमाला (Guatemala) की विजय लेटिन अमेरिका में साम्यवादियों की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। इन सभी सफलताओं के बाद भी लेटिन अमेरिका में साम्यवाद का जहाँ-तहाँ थोड़ा-बहुत प्रभाव है और इसको पश्चिमी देशों द्वारा कोई गम्भीर चुनौती नहीं समझी जाती। समुक्तराज्य अमेरिका ने अनेक बहुपक्षीय सन्धियों द्वारा लेटिन अमेरिका के राज्यों को हथियार तथा मैनिफेस्टो भेजे हैं। सभी सदस्यों की सहमति में अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) ने यहाँ साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

लेटिन अमेरिका के विकास की सबसे बड़ी बाधा यह मानी जाती है कि यहाँ के लोगों में सामाजिक चेतना नहीं है। इस प्रदेश में अभी तक किसी ऐसे नेतृत्व का जन्म नहीं हुआ जो सारे प्रदेश की सहमति प्राप्त कर विश्व राजनीति में उसका प्रयोग कर सके।

लेटिन अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका व अन्य क्षेत्र में वामपंथी प्रवृत्तियाँ¹

एक वक्त था जब लेटिन अमेरिकी देश अमेरिका की धड़कन समझ जाते थे। लेकिन क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने दो दर्जन साल पहले कुछ अलग हुरकत कर अमेरिका के इस मिशन को भेय्या साबित कर दिया। न केवल यही बल्कि उनके एक छापामार मित्र चेम्बेवारा और फ्रांसीसी बुद्धिजीवी रेजिस देब्रे (वर्तमान फ्रांसीसी सरकार में मंत्री) ने अपनी वामपंथी विचारधारा का जिस प्रकार फैलाव शुरू किया उससे अमेरिकी शासनतन्त्र में खलबली मच गई। इन दो छापामारों ने बोलीविया के जंगलों को अपना शरणालय बनाया और स्थानीय लोगों का (आज भी यहाँ पर मूल इन्डियन्स की संख्या बहुत है) सहयोग प्राप्त कर तत्कालीन सरकारों को

चुनौती दे डाली। बेशक अमेरिका के समर्थन से सतत और सक्रिय छापामार उन्मूलन प्रहार के कारण चेम्बेवारा मारा गया लेकिन जिन चिन्हों की छाप बोलीविया के जंगलों में वह छोड़ गये वह सिमट कर ही नहीं रह गई उसने ऐसा रास्ता बनाया जिसकी पगडंडिया आज कई लेटिन अमेरिकी देशों से होकर गुजरती है। बोलीविया में न तब स्थिरता थी और न ही आज है। शायद ही कोई सरकार पूरा साल वहाँ टिकती हो।

लेटिन अमेरिका को अक्सर अनिश्चित समुदायों का महाद्वीप माना जाता है। यहाँ के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों पर कुछ सामन्तवादियों का वर्चस्व है। निकारागुआ का सोमोजा परिवार अधिक विख्यात है। सामन्तवादी परिवारों का सभी क्षेत्रों पर इतना प्रभाव है कि उनकी मर्जी के बिना कोई सरकार चल ही नहीं सकती और न ही उनसे पूछे बिना सुधार किये जा सकते थे। ये सामन्ती परिवार जब चाहते कान्ति कराकर नई सरकार गठित करा देते और जिसे चाहते उसे सत्ता (होना) कर देते। यथास्थिति शायद उनकी नियति रही है। बहुविध समुदायों के कारण आन्विकारी प्रवृत्तियों का कभी अभाव नहीं रहा है। अमेरिका और लेटिन अमेरिका में एक बड़ा और महत्वपूर्ण अन्तर है। जहाँ अमेरिका और कनाडा में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, यूनान आदि देशों के लोग आकर बसे वहाँ लेटिन अमेरिकी देशों में निरन्तर युद्धों का जोर रहा। लेटिन अमेरिकी देश स्पेन और पुर्तगाल की बस्तियाँ ही बन कर रह गये। उन्हें धीरे-धीरे मुक्ति तो मिलती रही लेकिन औपनिवेशिक शक्तियाँ सदैव प्रभावशाली रहीं। यद्यपि आज ब्राहूँतीना वेनेजुएला, चीले, मैक्सिको और लेटिन सातीनी अमेरिका के आधुनिक देश माने जाते हैं तथापि कम से कम पन्द्रह देश आज भी ऐसे हैं जो पिछड़ेपन की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इन पाँच देशों को किसी पश्चिमी यूरोपीय देश से कम विवर्णित और स्थिर नहीं माना जाता। इन देशों की सामाजिक आधुनिकता और राजनैतिक स्थिरता के कारण अन्य पञ्चनी देशों ने भी जब उनके प्रवाह में बहने का प्रयास किया तो सामन्तवादी तबकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सामन्तवादी और सामन्तवादियों में जो रेखा खिंची वह बढ़ती चली गई। आज हालत यह है कि लेटिन अमेरिकी देशों में (यदि पाँच को छोड़ भी दिया जाये) बड़े पैमाने पर राजनैतिक अस्थिरता है और अर्थव्यवस्था जर्जर है।

निकारागुआ, पनामा, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होडूरस आदि देशों का राजनैतिक जीवन पहले की तरफ ही सकटपूर्ण स्थिति में है। आज भी निरंकुश सैनिक या सेना समर्थित सरकारें सत्ता में हैं और राजनीतिक बौने से दोखते हैं। सैनिक शासन के कारण लोग नागरिक अधिकारों से वंचित हैं। कमोवेश उन्हीं पाँच देशों में नागरिक अधिकार लोगों को उपलब्ध हैं (चीले में वह भी नहीं) या राजनैतिक पार्टियों का अस्तित्व है। लेकिन शुद्ध पैरसनल सरकारें वेनेजुएला और मैक्सिको में ही हैं। लेटिन अमेरिका में जिस प्रकार सत्ता पाने की लूटखसोट मची हुई है उससे कुछ प्रेक्षक उसे 'राजनीति विरोधी राजनीति' का नाम देते हैं। इन

तरह की निरकुश सैनिक शाही को भेदने का जो लोग या तबका प्रयास करता है उसे पहले तो सहमा सहमा और बाद में अधिक समर्थन प्राप्त होता है। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने बातिस्ता को निरकुश प्रवृत्तियों के विरुद्ध लोगों में जागरूकता पैदा करने में सफलता प्राप्त की (1 जनवरी 1959 में बातिस्ता सत्ताच्युत)। चीले में अस्थिरता के कारण डॉ साल्वाडोर अल्येंडे 1970 में राष्ट्रपति चुने गये (11 सितम्बर 1973 को जनरल आगुस्तो पिनोचेत द्वारा सत्ताच्युत)। निकारागुआ में सोमोसा का चार दशक का शासन उनके शासन के विद्रोहियों ने हिला दिया। अब साल्वाडोर में अभी भी दो विद्रोही तबकों में संघर्ष चल रहा है, हाँदूरस में तनाव की स्थिति है। खट्टेपात्र और हाँदूरस का परस्पर तनाव कौन सा रख अख्तियार करता है चर्चा का विषय है। बोनिविया, उरुग्वे, परागुए, कोलम्बिया भी अधिक स्थिर नहीं हैं।

प्रश्न यह उठता है कि इन विद्रोहियों या छापामारों को किसका सहयोग मिल रहा है। क्या सोवियत संघ या उसका मित्र क्यूबा इन विद्रोहियों की सहायता कर रहा है? यद्यपि इस तरह के हस्तक्षेप या समर्थन को प्रत्यक्ष तौर पर मानने को तैयार नहीं है तो भी इसमें दो राय नहीं कि जब से फिदेल कास्त्रो क्यूबा में जमे हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जा सका है। प्रयास न किये गये हो ऐसी बात तो नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यूबा तो अमेरिका का निकट पड़ोसी है। उसकी सीमा नाँध कर हाल तक लोग क्यूबा से अमेरिका में प्रवेश करते रहे हैं और अमेरिका के अपने नगर मियामी में क्यूबाइयों का एक अच्छा खासा उपनगर सा बस गया है जहाँ 'लघु हवाना' भी एच बस्ती है। वहाँ सभी के तौर तरीके क्यूबाई हैं। इस बस्ती के सभी लोग कास्त्रो विरोधी हो यह आवश्यक नहीं। कास्त्रो धुर मानसवादी है, यह तथ्यशुदा बात है। मार्क्सवादी आयेदे भी थे लेकिन एक तो अधिक उम्र के कारण उनमें कास्त्रो जैसी गतिशीलता नहीं थी और दूसरे चीले क्यूबा से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि वहाँ पर यूरोप के पश्चिमी भाग के लोगों की संख्या अधिक है। स्थानीय इन्डियन तो कम ही देखने को मिलेंगे। लिहाजा पीनोचेत को पहले आयेदे के विरुद्ध वातावरण बनाने और बाद में उन्हें सत्ता से हटाने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ी लेकिन जड़ता और वह भी राजनैतिक जड़ता वहाँ के लोगों को पसंद नहीं लिहाजा पीनोचेत के विरुद्ध भी कानाफूसी तो होती ही रहती है। मौका मिलने पर और सम्भवतया निकारागुआ और एल साल्वाडोर जैसे विद्रोहियों के संगठित हो जाने पर चीले में मानसवादी शक्तियाँ तीखी हो जायें तो असम्भव नहीं और छापामार निकारागुआ के विद्रोही और वर्तमान शासक पहले ही विद्रोही थे, उनका विश्वास भी सामन्तवादी समाज में था। उन लोगों ने सोमोजा जैसे शक्तिशाली नेता को हिला कर जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी अब उन में भी मतभेद बनते और बढ़ते जा रहे हैं। यद्यपि सोवियत संघ और क्यूबा की उन्हें आर्थिक और सैनिक महायुता मिल रही है लेकिन लोगों की समाजगत मोन सम्भवतया एक बार पुनः परिवर्तन की दृष्टि देखनी है। एक बार जड़ता हटने में

लोग प्रयोगवादी हो जाते हैं और उनके जहन में बेहतर विकल्प की चाह बलवती होने लगती है। अल साल्वाडोर में दो छापामार तबकों में मतभेदों के कारण ही निकारागुआ के लोगों को बल मिल रहा है, लेकिन इतना तो दोख रहा है कि बल तक सोमोजा की पीठ पर हाथ रखने वाले अमेरिका ने आज उस विद्रोही तबके की पीठ थपथपानी शुरू कर दी है जो वागवध विरोधी है। यहाँ तक कि उस तबके को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता का भी आश्वासन दिया गया है।

लातीनी अमेरिकी देशों का एक संगठन भी है जिसका मकसद एक दूसरे की सहायता करना है। लेकिन वर्तमान स्थितियों में वह केवल कागज की शोभा बन कर ही रह गई है। वास्तव में लातीनी अमेरिकी देशों की समस्याओं को जिस प्रकार राष्ट्रपति जान कर्नेडी ने समझा था और 'वे ऑफ गिम्स' की घटना ने लातीनी अमेरिकी देशों ने अमेरिका को जितना हितैषी की तरह देखा था उनकी मृत्यु के बाद घटनाक्रम बिल्कुल बदल गया। लिंडन जॉनसन और रिचर्ड निक्सन लातीनी अमेरिकी देशों के प्रति उदासीन रहे। जिम्मी कार्टर ने एक बार फिर लातीनी अमेरिकी देशों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हुए उन्हें यथोचित सहायता भी दी। लेकिन कर्नेडी और कार्टर के बीच की दूरी से इतनी रिक्तता पैदा हो चुकी थी कि कोई लातीनी अमेरिकी देश अमेरिका पर विश्वास करने को तैयार न था। लातीनी अमेरिकी देशों की अमेरिका के प्रति बढ़ती हुई अविश्वास की भावना को लगना है महसूस कर लिया है जिसके फलस्वरूप वर्तमान रीगन प्रशासन ने अपने द्वार पर वामपंथी प्रवृत्तियों के बढ़ते हुए शोर को लगता है सुना है। कल तक जिन देशों को अमेरिका सहायता देने को हिचकिचाता था आज उसने सहायता कोष का मुँह खोल दिया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या लातीनी अमेरिकी देशों की निरन्तर साक्षर होनी स्थानीय जनता के मन में अमेरिकी प्रशासन अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा जो आइजनहावर या कर्नेडी के समय था, यह अवश्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वामपंथी विचारधारा का प्रसार केवल विकासशील या अविश्वसित लातीनी अमेरिकी देशों तक ही सीमित नहीं बल्कि पश्चिम यूरोप के कुछ विभूत देश भी उसके प्रभाव की चपेट में आने लगे हैं। सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय देशों का एक अलग दायरा अवश्य है जिनकी सोच भी लगभग समान है। पश्चिम यूरोप के देशों के वामपंथियों की सोच पूर्व यूरोपीय देशों से বেশक जुदा है। लेकिन वामपंथी इसी बात से सन्तुष्ट हैं कि आज उस विचारधारा की न तो उस तरह जनदेवी की जाती है जैसी कि प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की जाती थी और न ही वामपंथी विचार के लोगों को हिराकत की नजर से देखा जाता है। सोवियत संघ जैसी शासन प्रणाली वाले देश, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, पोन्स्का, बुल्गारिया है लेकिन रोमानिया और यूगोस्लोवाकिया में भी वामपंथी विचारधारा की ही सरकारें हैं। इसी प्रकार अल्बानिया जो पहले सोवियत और बाद में चीन समर्थक हो गया था वह आज भी वामपंथी है लेकिन अपने अस्तित्व के प्रति वह सशंकित अवश्य रहता है। स्पानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सॉटियागो

वाट्सलो ने एक बार कहा भी था—'मस्कवा हमारे लिए रोम नहीं और न ही अक्तूबर (1917) हमारे लिए किसमस है।' इन घोषित वामपंथी देशों के अलावा जिन पश्चिमी देशों में इस विचारधारा की जड़े पुष्ता हो रही हैं वे हैं, फ्रांस, यूनान, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन आदि। इन देशों में वामपंथ का मतलब साम्यवाद नहीं या सोवियत संघ की शैली जैसा शासनतन्त्र नहीं बल्कि दोनों के बीच का रास्ता है। इन पश्चिमी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियाँ तो हैं ही, उसके अलावा समाजवादी पार्टियाँ भी हैं। कई देशों में दोनों वामपंथी पार्टियों में मतभेद भी है तो कहीं कहीं दोनों में तीखे मतभेद हैं। फ्रांस में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांस्वा मिस्तेरा को कम्युनिस्टों का सक्रिय समर्थन प्राप्त है। 1974 में तो दोनों पार्टियों ने मिल कर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन 1981 में दोनों पार्टियों के अलग-अलग उम्मीदवार थे। लेकिन जब समान सोच का समय आया तो दूसरे दौर के मतदान के दौरान कम्युनिस्टों ने अपना मत समाजवादी मिस्तेरा के पक्ष में डाल कर उन्हें जिस्कार देते से अधिक मत दिला दिये। इसी सहयोग के फलस्वरूप आज फ्रांस की सरकार में चार कम्युनिस्ट मंत्री हैं, 35 प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, सार्वजनिक क्षेत्रों का महत्व बढ़ रहा है और गाहेबगाहे ये नेता अमेरिका की नीतियों का विरोध कर अपने अलग अस्तित्व का परिचय भी दे जाते हैं। वामपंथियों के लिए इस लोक की भी कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इटली में कम्युनिस्टों और समाजवादियों दोनों का प्रभाव है। कई ऐसी नगरपालिकाएँ हैं जहाँ के महापौर कम्युनिस्ट हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार में उनके मंत्री नहीं, अलबत्ता बहुत-सी सरकारें 'बाहर से' उनके समर्थन पर टिकी रही हैं। फ्रांस की तरह यूनान में भी अक्टूबर, 1981 में संसद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता आद्रिस पापांद्रिऊ को बहुमत प्रदान कर भूतपूर्व प्रधान मंत्री और वर्तमान राष्ट्रपति कारमानलिस को पक्षोपेक्ष में डाल दिया है। लेकिन राष्ट्रपति के सर्वधानिक नेता होने के नाते वह प्रधान मंत्री के निर्णय को नकार तो नहीं सकते लेकिन दोनों में ठेठ जाने से अलबत्ता देश में गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। समाजवादी पापांद्रिऊ ने सत्तारूढ़ होने के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय और नेटो की अपने देश की सदस्यता का जायजा लेना शुरू कर दिया है। स्पेन और पुर्तगाल में तो समाजवादियों की सरकारें रही हैं लेकिन इन दोनों में कम्युनिस्ट पार्टियों का भी प्रभाव क्षेत्र खासा व्यापक है। दिलचस्प बात यह है कि इन पश्चिमी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने सोवियत संघ के अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया। पिछले वर्ष सोवियत संघ में वापिस सम्मेलन में भी कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ हालाँकि आम तौर पर पश्चिमी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता मस्कवा सम्मेलन में भाग लेते रहे हैं।

बहने को तो पश्चिमी जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ब्रिटेन की लेबर पार्टी को भी वामपंथी या वामोन्मुखी माना जाता है। लेकिन समय सरबने के साथ-साथ इनकी परिभाषा बदल गई है। आज इन दोनों पार्टियों में धुर और मध्यमार्थियों में इस प्रकार के मतभेद पैदा हो गए हैं जिनसे टूट का रूप ले लिया

है। लेबर पार्टी से टूट कर अस्तित्व में आने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के विचारों के टकराव की ही द्योतक है। पश्चिमी जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में जहाँ हाम्बुर्ग के भूतपूर्व महापौर क्नोज जैसे धुर वामपंथी विचारों के लोग हैं वहाँ हेल्मूट श्मिड्ट जैसे भी व्यक्ति नहीं जिन्हें अनुदारवादी प्रिन्चन डेमोक्रेटिक लोग 'हम स्थान' मानते हैं। लिहाजा आज विश्व में उस प्रकार का पैमाना नहीं रह गया है जिससे यह नापा जा सके कि प्रभु देश और व्यक्ति कितना वामपंथी है और कितना अनुदारवादी।

यदि हम अफ्रीका पर एक नजर डालें तो यह फर्क कुछ ज्यादा साफ हो जाता है। अफ्रीका में आज भी स्वाधीनता प्राप्ति की जड़ो जहद है। दक्षिण अफ्रीका के काले बहुसंख्यक शासन के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हैं। नामीबिया में स्वतंत्रता की मांग का नारा निरन्तर बुलन्द किए जा रहे हैं। स्वाधीनता संग्रामी इन छापामारों का भुकाव निस्सन्देह फिलहाल वामपंथ की ओर है। इन छापामारों की सोवियत संघ और क्यूबा आदि से सैनिक (ग्रन्थ और व्यक्ति दोनों) सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता भी कई स्रोतों से पहुँचती है। अंगोला, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे के स्वाधीनता संग्रामियों को भी सोवियत संघ से सानी सहायता मिल करती थी। आज भी वह सहायता जारी है, लिहाजा यहाँ के नेतृत्व का सोवियत संघ की ओर भुकाव अस्वाभाविक करार नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अफ्रीका के ये देश अपने आपको मुटुनिरपेक्ष और तटस्थ करार कर देते हैं तथापि नेतृत्व की सोच में वामपंथ का आभास मिलता ही है।

इन स्वाधीनता संग्राम के कारण सत्तारूढ होने वाले देशों के अलावा कुछ देश ऐसे हैं जिनमें सत्ता की उथल-पुथल से वामपंथी विचारधारा ने प्रवेश किया। इन देशों में इथियोपिया का नाम लिया जाता है। सम्राट हेले सिलासी की इथियोपिया पर पकड़ ढीली होने के बाद ही देश में लोकतन्त्र की बहाली को लेकर अराजकता पैदा हो गई है। एक के बाद एक कई नेता आए लेकिन पृथकतावादी इरीट्रिया मुक्ति मोर्चे की बलि चढ़ गए। अन्ततः मरियम में गिस्तु ने गृहयुद्ध की खपेट में ग्रन्थ इथियोपिया पर अपनी सत्ता के सूत्र पुस्तु किए। जब सोवियत संघ की यात्रा के बाद वह उनमें भरपूर आशवासन और सहायता लेकर लौटे तो उनमें गजब का आत्म-विश्वास था। कल तक का सोवियत मित्र सोमालिया आज बेगाना हो गया था। जब इथियोपिया और सोमालिया में खोलादेन की ज़ेबुर युद्ध हुआ तो इथियोपिया की विजय से अफ्रीका के इस क्षेत्र में (हार्न ऑफ अफ्रीका) मेगिस्तु अपने आपको सुदृढ़ पाने लगे। लिहाजा मेगिस्तु ने वामपंथ की जिम लीक को उलाघा यह बेगक रूसोन्मुखी है। इथियोपिया में सोवियत संघ के अतिरिक्त क्यूबा के भी सैनिक हैं। वैसे भी अफ्रीकी देश पश्चिमी समर्थक कम ही रहे हैं। वहाँ पर अपने-अपने प्रकार का विशेष अफ्रीकी समाजवाद है। यह समाजवाद भी सोवियत संघ के आस पास निकट है। घाना के संस्थापक डॉ. क्वासे एन्क्रूमा ने देश को रूस नेता ही डँचा दिया। बाद में सैनिक कान्तिपों से उसमें परिवर्तन अवश्य आया लेकिन सोवियत

संघ से उसकी निकटता कम नहीं हुई। तांजानिया के जूलियम न्यूरेरे, उगांडा के डॉ. मिन्टन ओबोटे, नाम्बिया के केनेथ वाउडा भी समाजवादी विचारों के नेता ही माने जाते हैं।

जहाँ तक एशियाई देशों का सम्बन्ध है आठवें दशक के अन्त से वामपंथी प्रवृत्तियों का प्रसार अधिक तेज गति से हुआ। 24 दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के हस्तक्षेप के बाद से ऐसा लगने लगा कि कहीं-कहीं एशिया भी तो पूर्वी यूरोप बनने नहीं जा रहा है। वास्तव में जब जहीर शाह को दाऊद खाँ ने अपदस्थ किया था तभी से वामपंथियों ने अपने संगठन को मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। यह बात भी भ्रमर है कि दाऊद खाँ को सत्ता से हटाने वाले तूर मुहम्मद तराकी के गुट तथा दूसरे अमीन गुट में अन्तर्बन्ध हो जाने से वामपंथियों में दरार पैदा हो गई लेकिन आज भी बबरक कारमाल का जो गुट सत्ता में है वह सोवियत संघ द्वारा 'घोषा' गया माना जाता है। लिहाजा अफगानिस्तान में राजशाही का स्थान वामपंथ ने ले लिया है।

अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में यद्यपि उस तरह की वामपंथी शक्तियाँ दृढ़ नहीं लेकिन ईराक और सीरिया की वाम पार्टियों को समाजवादी या वामपंथी ही कहा जाएगा। सैनिक शक्ति से सत्ता में आने वाली ये पार्टियाँ इस समय सोवियत संघ के अधिक करीब हैं। बेशक सोवियत संघ के सलाहकार वहाँ मौजूद हैं लेकिन उनकी शासन गैली अफगानिस्तान से दूर है। एक अन्य पड़ोसी देश ईरान है जो अमेरिका विरोधी तो है लेकिन सोवियत संघ का भी मुखर समर्थक नहीं। अपने हाल के बयानों से उसने अलबत्ता सोवियत संघ से सहयोग लेने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन जिन प्रकार पिछले दिनों ईरानी मुल्लाओं ने कम्युनिस्ट समर्थकों को खून-खून कर सरकारी पदों से हटाना शुरू किया है उससे लगता है कि अयातुल्ला खुमैनी सोवियत संघ पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं। इसका एक कारण अपदस्थ राष्ट्रपति बनीसदर और उनके समर्थक रवाजी द्वारा गठित निर्वाचित सरकार है। बहरहाल, वामपंथ की शाखाएँ तो ईरान में ही हैं। कहने को तो प्रेशक यहाँ तक कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक वामपंथियों का प्रसार हो जाएगा। ये वामपंथी प्रवृत्तियाँ कौसी होंगी यह अलबत्ता अटकलों का विषय है। कुछ लोग उसे मुस्लिम वामपंथ का नाम देते हैं तो कुछ सैनिक बनाम मुस्लिम वामपंथ का।

वामपंथ के इस फैलाव से चीन अलबत्ता परेशान सा दीखता है। जब से उसकी अमेरिका से दोस्ती हुई है तब से उसकी वामपंथी परिभाषा में भी अन्तर आया है। माओ और चाओ की मृत्यु के बाद से प्राधुनिकता का जो दौर शुरू हुआ है उससे उसकी वामपंथी प्रतिभा खण्डित तो नहीं हुई है लेकिन विरुद्ध अवश्य हुई है। एशिया में चीन का एकमात्र समर्थक देश उत्तरी कोरिया है। हाँ कम्बोडिया के पोन पोन और लाल खमेरों में अभी भी चीनी समर्थक मिल जाते हैं। हिन्दचीन के अन्य देशों में वर्तमान हेङ् सामरिक का कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस न केवल वामपंथी देश हैं बल्कि कुछ प्रेशक एशिया में उन्हें सोवियत संघ का 'उपग्रह' तक

करार देते हैं। ये तीनों देश चीन के लिए 'चुनौती' माने जाते हैं, पिछले दिनों चीनी और वियतनामी सैनिकों में मुठभेड़ के कारण सम्भवतया दोनों वामपथी गुटों ने अपनी-अपनी श्रेष्ठता मिट्ट कराने का प्रयास करना चाहा था और दोनों ने ही अपनी-अपनी पीठ थपथपायी थी। वास्तव में यही देश इस कोशिश में भी हैं कि उत्तरी कोरिया को अपने खेमे में लाया जाए। अभी तक उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। शायद वे इसी से सन्तुष्ट हैं कि वह भी वामपथी लोक पर अडिग है। उनमें सभी वामपथियों जैसा एवा दीखता है।

जहाँ तक अरब देशों का सम्बन्ध है मोटे तौर पर इराक, सीरिया, लीबिया की सरकारों का झुकाव वामोन्मुखी है। लेकिन सोवियत संघ इन्हें अपना स्थिर 'मार्क' नहीं मानता। खास तौर पर लीबिया के राष्ट्रपति मुघ्रवर गद्दाफी जिस प्रकार अपना पैतरा बदलते रहते हैं उन्हें तो गम्भीरता से नहीं लिया जा सकता क्योंकि राजनीतिक महत्त्व इन देशों और नेताओं का है। लिहाजा वामपथी शक्तियाँ अरब राष्ट्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करने की बराबर चाहवान रही हैं। इसी के फलस्वरूप दक्षिण यमन में उन्हें अपनी लोक चलाने में सफलता मिली भी है। बेशक सऊदी अरब के राजतन्त्री सैनिक कभी-कभी वहाँ अपनी गोटियाँ बिठाने का प्रयास करते हैं लेकिन दक्षिण यमन अभी तक वामपथियों की पक में ही आया है।

इस प्रकार वामपथ का, चाहे जैसा भी स्वरूप हो, जो दौर पिछले दशक से चल रहा है उससे इस विचारधारा के बढ़ते हुए समर्थकों का पता तो चल ही जाता है। उनकी कितनी सख्या है और उनकी छत्रछाया में कितने देश आते हैं इसका निश्चिन्त आकलन करना तो कठिन है, मोटा अंदाज ही लगाया जा सकता है। जितना अनुमान आज लगाया जाता है अगले दिन वह उनना ही गलत हो जाता है और इस प्रकार जोड़ बाकी की यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है और शायद जारी रहेगी।



ने सुरक्षा परिषद् में प्रश्न उठाया, किन्तु उसकी चाल सफल नहीं हुई। 1948 में हैदराबाद की रियासत का भारत में विलय हुआ। पाकिस्तान की अड़बेबाजी असफल रही। स्वतन्त्र भारत ने पुरानी सरकार के पूरे ऋण का भार सम्भाला जिनके अनुसार उसे पाँच वर्ष में पाकिस्तान से 300 करोड़ रुपये लेना था, लेकिन पाकिस्तान ने ऋण चुकाने का नाम तक नहीं लिया जबकि भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपये का चुकारा कर दिया। विस्थापित सम्पत्ति तथा अल्प-संख्यकों की रक्षा के सम्बन्ध में 1905 में जो नेहरू-लियाकत समझौता हुआ उसका पाकिस्तान की ओर से कभी पालन नहीं किया गया और पीड़ित हिन्दू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आते रहे। दोनों देशों के मध्य एक समस्या नदियों के पानी के सम्बन्ध में थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता से सितम्बर 1960 में सिन्धवेसिन के पानी के बँटवारे के बारे में दोनों देशों के बीच 'नहरी पानी समझौता' सम्पन्न हुआ। यह समझौता पाकिस्तान के लिए विशेष लाभदायक था। निष्पक्ष पर्यवेक्षकों को भी भारत के उदार दृष्टिकोण से आश्चर्य हुआ क्योंकि स्वयं उनको अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए सिन्धु के पानी की काफी आवश्यकता थी।

कश्मीर पर 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद से ही प. नेहरू ने निरन्तर यह असफल प्रयत्न किया कि दोनों राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार युद्ध न करने सम्बन्धी एक स्थायी समझौता हो जाए। भारत के शान्ति-प्रयत्नों को पाकिस्तानी अधिनायक खुशामद और कमजोरी समझने लगे। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने एक स्वर से भारत को दोषी ठहराया और भारत को दी जाने वाली अमेरिकी तथा ब्रिटिश सैनिक सहायता का भी तीव्र विरोध किया। यही नहीं पाकिस्तान ने चीन के साथ एक धूर्तनापूर्ण समझौता कर पाक अधिकृत कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग अवैधानिक रूप से चीन को दे दिया। भारत के विरोध का कोई फल नहीं निकला। सितम्बर 1963 में पाकिस्तान के बड़े जामूसी जाल का पता चला। नयी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास इस जामूसी षडयन्त्र का केन्द्र था जिसका उद्देश्य भारत को गुप्त सामरिक बातों की जानकारी करना था। भारत ने जामूसी में सम्बद्ध पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को भारत से हटाने का निश्चय किया, किन्तु पाक उच्च आ्युक्त के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार ने अपने निश्चय की घोषणा 5 दिन के लिए स्थगित कर दी। इसी बीच पाकिस्तान ने कराँची स्थित भारतीय दूतावास के प्रमुख अधिकारियों पर जामूसी करने का भूटा आरोप लगाकर उन्हें पाकिस्तान छोड़ देने की आज्ञा दे दी, भारत सरकार ने भी पाकिस्तानी अधिकारियों को भारत में निष्काशित कर दिया। पाकिस्तान ने इसे बदले की कार्यवाही कहकर भारत के विरुद्ध सूब विप-धमन किया। पाकिस्तान ने एक और घटना के सम्बन्ध में भारत के विरुद्ध अपनी जन्मजात शत्रुता का मुता परिचय दिया। 28 दिसम्बर 1963 को श्रीनगर की हजरत बान मस्जिद से पैगम्बर मुहम्मद साहब

का पवित्र बाल चोरी चला गया यद्यपि यह बाल मिल गया, पर पाकिस्तान ने इस घटना को लेकर बड़ा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाया ।

कश्मीर पर भारत-पाक तनाव बना रहा । पाकिस्तान ने 22 सितम्बर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण किया था और सुरक्षा परिषद् के प्रयत्नों से 1 जनवरी, 1949 से युद्धविराम होकर दोनों देशों के बीच समुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से तथा प्रत्यक्ष रूप से परस्पर वार्ता चल रही थी । प नेहरू की गुट-निरपेक्ष नीति से लिप्त समुक्तराज्य अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया, अतः समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका । पाकिस्तान ने अग्रलिखित मुख्य तर्कों का सहारा लिया—(1) कश्मीर का भारत में विलय भारत द्वारा प्रयोग की गई शक्ति और भय-प्रदर्शन का परिणाम था, (2) कश्मीर का भारत में विलय जनमत-संग्रह की शर्त पर आधारित था जिसे पूरा किए बिना कश्मीर स्थायी रूप से भारतीय संघ का अंग नहीं माना जा सकता, (3) कश्मीर जैसे मुस्लिमबहुल प्रदेश का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए, (4) जनमत-संग्रह के प्रश्न पर पाकिस्तान का समानता का अधिकार है तथा कश्मीर पर कोई भी निर्णय करने में भारत और पाकिस्तान को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, एवं (5) कश्मीर के महाराजा ने जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया था जो अवैध है ।

पाकिस्तान के सभी तर्क बेतुनियाद और बेतुके थे । कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण वैधानिक था क्योंकि राज्य के प्रमुख के हस्ताक्षर के उपरान्त ही उसका विलय भारत में किया गया था । कश्मीर के महाराजा ने भारत में विलय का प्रस्ताव भारत की शक्ति के भय से नहीं बल्कि इस डर से किया था कि पाकिस्तानी बर्कत उसकी रियासत को हड़पने वाले थे और रियासत की केवल भारत ही रक्षा कर सकता था । भारत ने प्रारम्भ से ही यह निश्चित मत व्यक्त किया कि कश्मीर का भारत में प्रवेश पूर्णतः सैद्धान्तिक है । इस सम्बन्ध में मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किए गए—(1) भारत में कश्मीर का विलय सन् 1947 के भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम में उल्लिखित प्रवेश-पत्रिका के अनुरूप पूर्णतः वैधानिक था, (2) कश्मीर की जनता ने स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित अपनी संविधान सभा के माध्यम से कश्मीर को भारत संघ का अभिन्न अंग घोषित कर दिया था, अतः जनमत-संग्रह की बात स्वतः ही पूर्ण हो गयी; (3) आत्म-निर्णय एक लोकतान्त्रिक प्रश्न है जिसका प्रयोग राज्यों को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए नहीं किया जाता; (4) स्वयं पाकिस्तान ने जिन राज्यों का विलय किया, उन्हें कभी आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं दिया; (5) जो राष्ट्र अपनी जनता को भी लोकतान्त्रिक अधिकार नहीं दे पाया है, उसके लिए आत्म-निर्णय की बात कहना बेहूदा है; (6) एक आक्रमणकारी राष्ट्र विलय की बात नहीं कर सकता; (7) यह भी सर्वथा अवैधानिक है कि पाकिस्तान ने अतःपूर्वक कश्मीर के जिस भाग पर कब्जा किया उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे राष्ट्र चीन को अवैध रूप से सौंप दिया; (8) भारत ने कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की केवल

इच्छा ही व्यक्त की थी वह विलय की पूर्ण शर्त नहीं थी तथा जनमत संग्रह का आश्वासन कश्मीर के शासक को दिया गया था, एक तृतीय पक्ष पाकिस्तान को नहीं, (9) जनमत संग्रह की बात पाकिस्तान द्वारा कश्मीर से अपनी सेनाएँ हटाने के बाद पूरी करने को कही गई थी, लेकिन पाक-कौजों की उपस्थिति स्वयं जनमत-संग्रह के मार्ग में बाधा बनी हुई रही है, और अब कश्मीर में स्वतन्त्र चुनाव हो जाने के बाद जनमत-संग्रह का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है; (10) कश्मीर में मुस्लिम बहुमत के आधार पर जनमत संग्रह की बात गलत है, भारत जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धान्त को मान्यता नहीं देता, एवं (11) पाकिस्तानी दुराग्रह स्वीकार करने का अर्थ सम्पूर्ण देश और कश्मीर की शान्ति भंग करना तथा भारत में कश्मीर-विलय के कश्मीरी जनता के निर्णय का स्पष्ट अपमान करना है। भारत ने स्पष्ट रूप से यह स्थिति स्पष्ट कर दी कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है।

पाकिस्तान के शासकों ने न तो पण्डित नेहरू के प्रधान मन्त्रित्वकाल में अपनी भारत विरोधी नीति छोड़ी और न बाद में ही। 27 मई, 1964 को नेहरू की मृत्यु हो गई।

शास्त्री युग (मई 1964—जनवरी 1966)

नेहरू के उत्तराधिकारी श्री लालबहादुर शास्त्री ने नेहरू के आदर्शवाद को निभाते हुए राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यथार्थवादी नीति अपना कर अपनी कूटनीतिज्ञता का सुन्दर परिचय दिया। श्री शास्त्री ने 15 अगस्त, 1964 को स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के साथ 'युद्ध न करने का समझौता' करने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान के शासकों के कानों में जूँ तक नहीं रेंगी। कच्छ पर और बाद में कश्मीर तथा भारत पर होने वाले पाकिस्तानी आक्रमणों ने मिथ्य कर दिया कि पाकिस्तानी नेता भारत के प्रति शत्रुता और युद्ध की नीति से तब तक डिगने वाले नहीं हैं जब तक उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा।

1965 में पाकिस्तान ने भारत पर दो प्रबल सैनिक आक्रमण किए, इनमें पहला आक्रमण मार्च-अप्रैल, 1965 में कच्छ पर हुआ, दूसरा अगस्त-नितम्बर, 1965 में कश्मीर पर। कच्छ की खाड़ी एक दलदलीय क्षेत्र है। पाकिस्तान ने इस प्रदेश के उत्तरी हिस्से में पहले एक सड़क बना ली और बाद में भारतीय सीमा में अपनी स्थायी चौकियाँ स्थापित कर ली। उसने भारत के विरोध-पत्रों की न केवल उपेक्षा कर दी बल्कि गुजरात के एक बड़े क्षेत्र पर भी अपने अधिकार का दावा किया। पाकिस्तान का यह दावा ऐतिहासिक और वैधानिक रूप में सर्वथा वाक्योक्ति इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पहले से निर्धारित हो चुकी थी। दोनों देशों के बीच बार्ना चालू थी जि 9 अप्रैल, 1965 को पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी ने मरदार नामक भारतीय चौकी पर हमला बोल दिया। 24 अप्रैल को कच्छ पर पाक सेना का आक्रमण हो गया। भारत-पाक संघर्ष को रोकने के लिए ब्रिटेन ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा जिसे भारत ने मान लिया, लेकिन पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया। अग्न में,

लन्दन में होने वाले राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन के अवसर पर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री विम्बन के प्रयत्नों से भारत और पाकिस्तान के बीच कच्चा के प्रश्न पर 30 जून, 1965 को एक समझौता हो गया जिसमें अश्लिखित बातों का उल्लेख था—1. 1 जुलाई, 1965 से युद्ध बन्द कर दिया जाए। 2. दोनों देशों की सेनाएँ 7 दिन के भीतर पीछे हटा ली जाएँ और अपनी 1 जनवरी, 1965 की स्थिति पर लौट जाएँ। 3. सीमा-विवाद के प्रश्न का समाधान पहले मन्त्रियों की बातों द्वारा किया जाए और इस प्रकार की बातों सफल न होने पर यह प्रश्न एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण को सौंपा जाए। सितम्बर, 1967 में न्यायाधिकरण ने अपना काम शुरू किया और 19 फरवरी, 1968 को उसने अपना निर्णय दे दिया। इस निर्णय के अनुसार विवाद-ग्रस्त क्षेत्र का 90% भाग भारत को दिया गया और केवल 320 वर्ग मील का प्रदेश पाकिस्तान को प्राप्त हुआ। पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र प्राप्त हो गया। यद्यपि न्यायाधिकरण का निर्णय कुल मिला कर भारत के पक्ष में था, तथापि पाकिस्तान के साथ विशेष रियायत की गई थी। भारत सरकार ने इस निर्णय को 'राजनीतिक कारणों से प्रेरित' बता कर इसकी निन्दा की। भारत के सामने वक्त निभाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत सरकार ने कूटनीतिक चालबाजी की जगह नैतिकता को उच्च गमभा।

कच्चे समझौते की स्याही सूखने भी न पायी थी कि अगस्त, 1965 में पाकिस्तान ने व्यापक तोड़-फोड़ करने, अराजकता फैलाने और सैनिक ठिकानों तथा उद्योग स्थलों को नष्ट करने के लिए कश्मीर में सशस्त्र घुसपैठिए भेज दिए। इस पर भारतीय सेना ने तेजी से घुसपैठियों का सफाया कर युद्धविराम रेखा के उन महत्वपूर्ण पहाड़ी और जंगली प्रतिष्ठानों पर बरबाद कर लिया जहाँ से घुसपैठिए भारत में प्रवेश करते थे। पाकिस्तान एक हारे हुए जुझारी की तरह बौखला उठा। 1 सितम्बर, 1965 को पाकिस्तान ने विपुल टैंक शक्ति के साथ कश्मीर के छत्र क्षेत्र पर प्रचानक ही भीषण आक्रमण कर दिया। भारत के भीषण प्रत्याक्रमण ने पाकिस्तान को छठी का दूध पाद करा दिया। भारत ने पाक के विरुद्ध सम्पूर्ण सीमा पर तट मोर्चे खोल दिए। 15 सितम्बर तक पाकिस्तान की वायु-शक्ति की कमर टूट गई। पाकिस्तान को प्राप्त अमेरिकी पेंटन टैंकों का कश्मिर बन गया और पाकिस्तान की पराजय सन्निकट दिखाई देने लगी। भारत पाक-युद्ध 23 सितम्बर, 1965 तक चला और अन्त में संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से 23 सितम्बर, को 3 1/2 बजे प्रातः काल युद्ध-विराम हो गया। युद्ध-समाप्ति पर लगभग 750 वर्गमील पाकिस्तानी क्षेत्र भारत के अधिकार में था जबकि आकस्मिक आक्रमण का लाभ उठा लेने के कारण 240 वर्गमील का भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में रह गया था। भारत ने निरन्तर विजयी होने हुए भी युद्ध-विराम स्वीकार कर यह सिद्ध कर दिया कि वह एक शान्तिप्रिय राष्ट्र है। युद्ध से यह पुनः स्पष्ट हो गया कि साम्यवाद के विरोध के नाम पर पाकिस्तान को दी गई विशाल अमेरिकी सैनिक सहायता का किस प्रकार एक शान्तिप्रिय लोकतान्त्रिक राष्ट्र के

विरुद्ध दुष्प्रयोग किया जा सकता है। मुद्द-विराम के बाद भी पाकिस्तान भड़काने वाली कार्यवाहियों से बाज नहीं आया और घाए दिन सीमा-उल्लंघन की घटनाएँ जारी रही। सोवियत प्रधानमंत्री कोसीगिन के दोनों देशों ने शीर्षम्य नेताओं की प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा ताश्कन्द सम्मेलन की व्यवस्था की। 10 जनवरी, 1965 को 9 बजे रात्रि को श्री अयूब खान और श्री शास्त्री ने एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर कर दिए जो 'ताश्कन्द घोषणा' के नाम से विख्यात हुआ।

इन्दिरा युग (जनवरी 1966—मार्च 1977)

श्री शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद पं. जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री बनी। अल्पकालीन शान्ति के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ पुनः छेड़छाड़ प्रारम्भ कर दी। वह न केवल सीमान्त पर छुटपुट छेड़छाड़ करता रहा बल्कि भारत की वायुसेना का भी अतिक्रमण करता रहा। कश्मीर पर पाकिस्तानी रवैया पूर्ववत् रहा। अप्रैल, 1966 में पाकिस्तान कश्मीर समस्या को पुनः सुरक्षा परिषद् में ले गया। सुरक्षा परिषद् कुछ न कर सकी। 22 सितम्बर, 1969 में मोरक्को की राजधानी रबात में इस्लामी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। पाकिस्तान के विरोध के कारण सम्मेलन के आयोजकों ने भारत को निमन्त्रण नहीं भेजा। इस पर भारत की ओर से कूटनीतिक प्रयत्न किए गए और अन्ततोगत्वा उसे सम्मेलन के आयोजकों ने भारत को निमन्त्रण प्राप्त हो गया। पाकिस्तान ने सम्मेलन में भारत के भाग लेने पर सम्मेलन के बहिष्कार करने और लौट जाने की धमकी दी और मोरक्को, जोर्डन आदि उसके अरब मित्रों ने उसका पूरा साथ दिया। केवल संयुक्त अरब गणराज्य का ही समर्थन भारत के पक्ष में रहा। वास्तव में रबात में जो कुछ हुआ वह भारत का राष्ट्रीय अपमान था। पाकिस्तान निरन्तर भारत विरोधी कार्यवाहियाँ करता रहा। 30 जनवरी, 1971 को इण्डियन एयर लाइन्स के एक यात्री विमान का अपहरण कर जबरन लाहौर हवाई अड्डे पर उतारा गया। भारत में तीव्र रोष की लहर दौड़ गई और सरकार ने पाकिस्तानी विमानों के भारतीय प्रदेश से होकर उड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

पाकिस्तान आन्तरिक अराजकता का भी शिकार था। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति आन्दोलन में जोर पकड़ा। पाकिस्तानी शासकों ने इस जनमुक्ति आन्दोलन को भारत के पड़ोस का परिणाम बतलाया। एक तर्फ तो इसे भारत-पाक समस्या के रूप में उधाला गया और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तानियों पर घोर अत्याचार तथा अमूल्य हत्याकाण्ड का त्रम खालू रखा जिससे लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए। इस प्रकार पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध भीषण आर्थिक विद्रोह छेड़ दिया। परिस्थिति बिगड़ती गई। पाकिस्तान में भारत से मुद्रा छेड़ने का उन्माद प्रबल होना गया और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही सीमान्तों पर पाक सेनाएँ घाए दिन छुटपुट

हमले करने लगीं। आखिर 3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर अचानक ही भीषण हवाई हमला बोल दिया।

भारत ने पाकिस्तान को एक न भूलने वाला सबक सिखाने का निश्चय करके विद्युत गति से प्रत्याक्रमण किया और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही मोर्चों पर जल, घस और नभ पर पाकिस्तान के सैन्य तन्त्र को भीषण क्षति पहुँचाई। पश्चिमी मोर्चों पर युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर लड़ा गया और पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तथा 'मुक्तिवाहिनी' की संयुक्त कमान ने भारतीय ले जनरल जगजीतसिंह अरोड़ा के नेतृत्व में कहर ढा दिया।

युद्धकाल में 5 दिसम्बर को सुरक्षा परिषद् की आपात्कालीन बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह 'पूर्वी पाकिस्तान' में क्रान्तिकारियों को सहायता देकर पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखण्डता पर प्रहार कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि समरसेन ने पाक आरोपों का तीव्र विरोध किया। सोवियत रुम के बार-बार बीटो के कारण सुरक्षा परिषद् में भारत-विरोधी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इन्हीं बीच 6 दिसम्बर को श्रीमती गांधी ने भारतीय संसद् में 'बंगलादेश गणराज्य' के उदय की सूचना दी। 'बंगलादेश' को मान्यता देकर श्रीमती गांधी ने समस्या को बिल्कुल एक नया मोड़ दे दिया और संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा सम्पूर्ण विश्व को बताना दिया कि भारत किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन को नहीं वरन् एक स्वतन्त्र राज्य की वंश सरकार को सहायता दे रहा है जिसके साथ 'नाटो' जैसा कोई सैनिक समझौता न होने पर भी भारत की पूर्ण सहानुभूति है। भारत पाक युद्ध केवल 14 दिन चला और 16 दिसम्बर, 1971 को बंगलादेश की राजधानी ढाका में पाक सेना के ले जनरल ए. ए. के नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। पूर्वी मोर्चे पर लगभग 1 लाख पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की लगभग 14 सौ वर्गमील भूमि पर कब्जा कर लिया गया। पाक सैनिकों के आत्मसमर्पण के तुरन्त बाद ही श्रीमती गांधी ने 17 दिसम्बर की रात्रि के 8 बजे 'एकपक्षीय युद्ध-विराम' की घोषणा करते हुए पाक-राष्ट्रपति जनरल याहिया खान से युद्धबन्दी प्रस्ताव को स्वीकार करने की प्रतीति दी। पाकिस्तान के लिए तो यह एक वरदान था जिसे याहिया खान ने तुरन्त के स्वीकार कर लिया।

भारत ने पराजित और विखण्डित पाकिस्तान की दुर्दशा का कोई अनुचित लाभ न उठाकर इस बात का प्रयत्न किया कि दोनों देश पारस्परिक बातों द्वारा अपने सभी विवादों का समाधान कर उपमहाद्वीप में मैत्री के एक नए युग का सूत्रपात करें। काफी विचार-विमर्श के बाद आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला (भारत) में जून, 1972 के अन्तिम सप्ताह में एक शिल्लर सम्मेलन के आयोजन का निश्चय हुआ। शिमला वार्ता 18 जून से 3 जुलाई तक चली। 3 जुलाई को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हो गए।

यह तथ्य बिया गया कि दोनों पक्ष आपसी वार्ता द्वारा अपनी समस्याओं को हल करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का अतिभ्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे के प्रति घृणापूर्ण प्रचार नहीं करेंगे, पारस्परिक सम्पर्क सेवाओं की पुनः स्थापना करेंगे, दोनों पक्षों की सेनाएँ अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर लौट जाएँगी, और दोनों पक्ष बिना एक-दूसरे की स्थिति को क्षति पहुँचाए जम्मू-कश्मीर में 17 दिसम्बर, 1971 को हुए युद्ध-विराम की नियन्त्रण रेखा को मान्यता देंगे। शिमला सम्मेलन के बारे में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए। आलोचकों ने 'जवानों के बलिदान की उपेक्षा' और 'जीती हुई भूमि' लौटाने के निश्चय पर तीव्र विरोध प्रकट किया। श्री वाजपेयी ने इस सम्मेलन में सरकार की बुद्धि का दिवालियापन देखा कि पाकिस्तान 69 वर्गमील क्षेत्र खाली करेगा जबकि भारत 5,139 वर्गमील पाकिस्तानी इलाका देगा। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि विरोधी पक्ष की आलोचनाओं में देशभक्ति की गुंज थी। किन्तु शिमला-सम्मेलन का मूल्यांकन करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए था कि सम्मेलन में भारत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे राष्ट्रीय सम्मान को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँची हो। श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने 13 जुलाई, 1972 के अपने भाषण में लोकमभा में यह विश्वास प्रकट किया कि शिमला-सम्मेलन में दोनों देशों का भला मिलकर चलने में ही है। भारत को शान्ति के लिए लड़ना है और उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए जो शान्ति की ओर ले चले। भारत किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार है, किन्तु इन बातों पर अवश्य विचार करना चाहिए कि क्या शान्ति सम्भव नहीं है।

शिमला-सम्मेलन के बाद भारत और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच सम्बन्ध सुधारने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई। बाघाओं के बावजूद धीरे-धीरे प्रगति हुई। जम्मू-कश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण रेखा को अन्तिम रूप में अंकित करने के उपरान्त दोनों पक्षों की सेनाएँ अपने-अपने स्थानों पर लौट गईं। पाकिस्तानी युद्धबन्दियों तथा अन्य मानवीय समस्याओं पर घने स्तरी पर बातचीत के दौर चले और अगस्त में 28 अगस्त, 1973 को भारत और पाकिस्तान में एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार पाकिस्तान से सभी बंगालियों, बंगलादेश से काफी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों और भारत से उन 195 युद्धबन्दियों को छोड़कर जिन पर बंगलादेश में मुकदमा चलाया जाना था, शेष सभी युद्धबन्दियों को जन्दी ही एक साथ बदला-बदली करने का निर्णय लिया गया।

शिमला-सम्मेलन में यह तथ्य बिया गया था कि कश्मीर के प्रश्न का स्थायी समाधान पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण और पूर्ण शान्ति स्थापना के बाद ही निकालना है, किन्तु सितम्बर, 1973 में मुद्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष अपने भाषण में फिर कश्मीर की रट लगाई। नवम्बर, 1973 में पाक प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान अधिभूत कश्मीर के दौरे के समय कुछ ऐसे बयान जारी किए जो शिमला सम्मेलन के प्रावधानों के विपरीत थे।

विभिन्न प्रयासों से बंगलादेश के प्रति पाकिस्तान का रवैया बदलता गया और अगस्त में 22 फरवरी, 1972 को पाकिस्तान ने भी बंगलादेश को मान्यता दे

दो। भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपराधियों के सम्बन्ध में अप्रैल, 1974 में एक समझौता हुआ किन्तु इसके बाद ही पाकिस्तान ने फिर तनाव का वातावरण बनाना शुरू कर दिया। 18 मई, 1974 को जब भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया तो श्री मुद्दो ने घोषणा की कि यदि भारत अणुबम बनाता है तो पाकिस्तान भी अणु बम बनाएगा, चाहे उसे धास-पात खाकर या भूखा जीवित रहना पड़े। श्रीमती गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अणु शक्ति का विकास रचनात्मक उद्देश्यों के लिए कर रहा है, किन्तु पाकिस्तान और उसके हिमायती राष्ट्रों के गले यह बात नहीं उतरी। श्रीमती गांधी ने श्री मुद्दो को एक पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच अनाक्रमण सन्धि का प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे गुरन्त ठुकरा दिया।

युद्ध के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच डाक, दूर-संचार और यात्रा सुविधाएँ समाप्त हो गई थी। सितम्बर, 1974 में इस्लामाबाद में दोनों पक्षों ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर करके इन सुविधाओं को तत्काल जारी करने का निर्णय लिया। फरवरी, 1975 में अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड ने पाकिस्तान को पुनः अमेरिकी हथियार प्रदान करने की घोषणा की तो श्री मुद्दो भारत के साथ दो-दो हाथ करने की बात करने लगे। सन्दन रिचम पश्चिम सैनिक विशेषज्ञों तक ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान जिस प्रकार आतंकवाद का सग्रह कर रहा है और अपने रक्षा व्यय में वृद्धि कर रहा है वह उसी वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टि से बिल्कुल अननुचित है। अगस्त, 1975 में बंगलादेश में शेर मुजीबुर्रहमान की सरकार को हिमापूर्व हटा दिए जाने के बाद पाकिस्तान के प्रचार माध्यमों ने अपने भारत-विरोधी आन्दोलन को एक नया रूप देते हुए यह कहा कि हो सकता है कि भारत बंगलादेश में हस्तक्षेप करे। भारत सरकार ने इस वैभनस्यपूर्ण एवं निन्दात्मक प्रचार-आन्दोलन की ओर पाकिस्तान का ध्यान आकृष्ट किया क्योंकि यह शिमला-समझौते के विपरीत था और सम्बन्धों को सामान्य बनाने के मार्ग में अड़चन सिद्ध हो रहा था। अगस्त, 1975 में ही पाकिस्तान ने पाक-अधिकृत कश्मीर के लिए एक परिषद् की स्थापना की जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान सरकार के पास अधिकृत कश्मीर पर अपने नियन्त्रण को पहली बार सस्थागत व्यवस्थित रूप दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि इस परिषद् की स्थापना करने की उसकी कार्यवाही शिमला-समझौते का उल्लंघन है क्योंकि यह जम्मू तथा कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत प्रदेशों की स्थिति में एकपक्षीय परिवर्तन है। कश्मीर की समस्या की शान्तिपूर्वक द्वि-पक्षीय तरीके से सुलझाने के लिए शिमला-समझौते की शर्तों के अनुसार वचनबद्ध होने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के निर्जीव प्रस्तावों में पुनः अन्तर्राष्ट्रीय हथि जगाने की कोशिश की। टीर्की और कम्बोडिया के राज्याध्यक्षों की पाकिस्तान-पात्राओं की समझौते पर जारी की गई संयुक्त विज्ञापितियों में भी इस दाशय का उल्लेख किया गया।

वर्ष 1976-77 में दोनों देशों के सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी। दोनों पक्षों ने निजी क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार चालू करना स्वीकार

किया, जुलाई, 1976 में दोनों देशों के बीच हवाई सम्पर्क पुनः चालू हुआ और दोनों देशों के राजदूतों ने अपने-अपने प्रत्यक्ष-गत्र प्रस्तुत किए। कई दिशाओं में सम्पर्क पुनः स्थापित हुए जो बीच के कई वर्षों में रुके रहे थे।

जनता पार्टी का शासन (मार्च, 1977-दिसम्बर, 1979)

जनता सरकार ने नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के विशेष प्रयत्न किए। विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान और चीन की यात्राएँ करके इनके साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने का प्रयास किया। विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी ने अप्रैल, 1977 में ही पाकिस्तान के मामले में युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव रखा था, किन्तु पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति पुनः टाल दी। फरवरी, 1978 में भारतीय विदेश मन्त्री ने पाकिस्तान की यात्रा की। पिछले 12 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मन्त्री की यह पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। सीमा पर स्थिति 1977 में पूरे वर्ष सामान्य बनी रही। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का शुभारम्भ भी हुआ। अप्रैल, 1978 में पाकिस्तान के बंदेशिक मामलों के सलाहकार श्री आगाशाही की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जबकि सत्ताल पन बिजली परियोजना के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर हुए, यह एक ऐसी समस्या थी जो विगत 8 वर्षों में अनुसूचित चली आ रही थी। सितम्बर, 1978 में एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भारत ने पाकिस्तान को 5270 टन गेहूँ का बीज देना तय किया। पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों को सामान्य बनाने और इसे आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी रहे और इस सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई।

**श्रीमती गांधी के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद
भारत-पाक सम्बन्ध (फरवरी, 1982 तक)**

श्रीमती गांधी के पुनः सत्तारूढ़ होने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक ने अपने सन्देश में शिमला-समझौते के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया और दोनों देशों के बीच सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की आशा प्रकट की। फरवरी, 1980 में विदेश सचिव श्री साठे पाकिस्तान गए। जनवरी तथा मई, 1980 में इस्लामी विदेश मन्त्रियों के सम्मेलनों में राष्ट्रपति जिया द्वारा कश्मीर के मामले के अनावश्यक उल्लेख से भारत को दुःख और निराशा हुई क्योंकि ऐसा उल्लेख शिमला-समझौते की भावना के अनुरूप नहीं था। पाकिस्तान द्वारा समुक्त राष्ट्रमण्डल में कश्मीर समस्या की चर्चा पर भारत ने अपनी तीव्र प्रतिनिध्या व्यक्त करते हुए इसे भारत की प्रादेशिक अखण्डता पर आघात बताया। 1980-81 के दौरान, बावजूद आपसी विचार-विमर्श के, पाकिस्तान की कुछ कार्यवाहियों की ओर से भारत चिन्तित रहा। पाकिस्तान ने, न केवल अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का उल्लेख करके भारत के आन्तरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप किया बल्कि अपनी गैरनिरास्यता को काफी विस्तृत करके क्षेत्रीय स्थायित्व पर दुष्प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। दिसम्बर, 1981 में अमेरिकी सेनेट ने रीगन प्रशासन द्वारा

पाकिस्तान को आधुनिकतम एफ-16 विमान देने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान द्वारा अन्धधुन्ध सैनिक शक्ति में वृद्धि भारत के लिए खतरे और चिन्ता का विषय है। फरवरी, 1982 में रक्षा मन्त्री आर. वेंकटरमन ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“हमारी चिन्ता इग बात से अवश्य बढ गई है कि पाकिस्तान ने अपनी जहूरतों से ज्यादा आधुनिकतम हथियार एकत्र कर लिए हैं। भारत पूरी ईमानदारी के साथ अनाक्रमण सन्धि करने के लिए बात चला आ रहा है।”

भारत और चीन

भारत और चीन दो घनिष्ठ मित्रों के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन 1962 में चीन ने भारतीय सीमान्तों पर आक्रामक आक्रमण कर इस मित्रता को धूल में मिला दिया। आज चीन भारत की कुछ भूमि पर अधिकार जमाए हुए है और भारत की ओर से सम्बन्ध सुधार के प्रयत्नों के बावजूद भारत के प्रति अशुनापूर्ण रुख अपनाए हुए है।

नेहरू-युग में भारत-चीन सम्बन्ध (1947-मई, 1964)

भारत ने साम्यवादी चीन के प्रति प्रारम्भ से ही मैत्री और सुष्टिकरण की नीति अपनाई। उसने चीन को मान्यता प्रदान की और संयुक्त राष्ट्रमंडल में उसके प्रवेश का जोरदार समर्थन किया। अक्टूबर, 1950 में ही तिब्बत में प्रवेश कर चीन ने अपने वास्तविक इरादों का संकेत दे दिया था, लेकिन भारत ने चीनी इरादों को समझने में मूल की। जब भारत सरकार ने तिब्बत में उसके प्रवेश की ओर चीनी सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो 30 अक्टूबर, 1950 को चीन की ओर से भारत को कठोर शब्दों में उत्तर दिया गया—“पश्चिम की साम्राज्यवादी नीति से प्रभावित भारत, चीन के अन्तर्देशीय मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस न करे।” भारत की सुष्टिकरण की नीति की हद तब हो गई जब 29 अप्रैल, 1954 को चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता कर भारत ने तिब्बत में प्राप्त अपने बहिर्देशीय अधिकार (Extra-territorial Rights) चीन को सौंप दिए और बदले में स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तिब्बत में चीन की प्रभुसत्ता को स्वीकार करना भारत सरकार की भारी मूल थी। समझौते की प्रस्तावना में दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास प्रकट किया। इन्हीं सिद्धान्तों का 1953 में बान्गुंग सम्मेलन में विस्तार किया गया। 1954 में चीनी प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई भारत आए और अक्टूबर, 1954 में पं. नेहरू ने चीन की यात्रा की।

चीन विभिन्न रूप से भारत के साथ सीमा-विवाद उठाता रहा और तब 20 अक्टूबर, 1962 को उसने भारत पर विनाश पैमाने पर आक्रामक आक्रमण कर भारत की भिन्नता का बदला चुकाया। पं. नेहरू की आशाओं और नीतियों पर यह घातक चोट थी। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच व्यावहारिक रूप से मान्य सीमा को मैकमोहन रेखा (McMohan Line) के नाम से जाना जाता है। अप्रैल, 1914 में भारत और तिब्बत तथा तिब्बत और चीन के बीच

सीमा-निर्धारण के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत सचिव आर्थर हेनरी मेकमोहन ने भाग लिया। शिमला सन्धि में यह तय हुआ कि (1) तिब्बत पर चीन को Suzerainty रहेगी, लेकिन बाह्य तिब्बत (Outer Tibet) को अपने कार्य में पूरी स्वतन्त्रता होगी, (2) चीन तिब्बत के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा; एवं (3) तिब्बत को चीन अपने राज्य का प्रान्त कभी घोषित नहीं करेगा। बाह्य तिब्बत और भारत के बीच ऊँची पर्वत श्रेणियों को सीमा मानकर एक नक्शे को लाल से चिह्नित कर दिया गया, जिसमें तीनों प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। इसी सीमा को मेकमोहन रेखा की संज्ञा दी गई। जब कभी सीमा विवाद उठा तो चीन ने इसी रेखा का समर्थन किया। 1959 से पूर्व उसने इस विषय में कोई आपत्ति नहीं उठाई। भारत-चीन सीमा-विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में यह भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत को स्वाधीनता प्राप्त करने के साथ-साथ उत्तराधिकार के रूप में तिब्बत में अनेक बहिर्देशीय अधिकार भी प्राप्त हुए थे। साम्यवादी चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता और भारत के बहिर्देशीय अधिकारों का कोई सम्मान न कर 7 अक्टूबर, 1950 को तिब्बत में अपने सैनिक भेज दिए। भारत द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर 30 अक्टूबर को चीन ने इसकी कठोर शब्दों में उपेक्षा की। चीन ने जो नए नक्शे प्रकाशित किए उसमें भारत की लगभग 50 हजार वर्गमील सीमा चीनी प्रदेश के अन्तर्गत दिखाई और नेहरू द्वारा यह प्रश्न उठाए जाने पर चीनी प्रधान मन्त्री ने कहा कि ये नक्शे राष्ट्रवादी सरकार के पुराने नक्शों की नकल हैं समय मिलते ही इन्हें ठीक कर दिया जाएगा। चीन भारत के साथ मुनियोजित ढंग से अपने विवादों को उग्र कर बनाता रहा और भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करता रहा। जुलाई, 1962 में गलवान घाटी की भारतीय पुलिस चौकी को चीनियों ने घेरे में ले लिया। सीमान्त पर चीनी सैनिक कार्यवाही बढ़ने लगी और भारतीय सैनिक चौकियों को घेरा जाने लगा। फिर 20 अक्टूबर, 1962 को प्रातःकाल भारत की उत्तरी सीमा के दोनों आँचलों पर चीन ने भीषण आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाएँ इन आक्रामक आक्रमण से सम्भलें तब तक चीन ने काफी भारतीय भूमि और सैनिक चीनियों पर कब्जा कर लिया।

भारत द्वारा सम्भल कर प्रत्याक्रमण करने से पूर्व ही चीन ने अक्वमात ही 21 नवम्बर, 1962 को एक पक्षीय युद्ध-धिराम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही चीन ने एक द्वि-सूत्रीय योजना भी घोषित की—(1) चीनी सेनाएँ 7 नवम्बर, 1959 की 'वास्तविक नियन्त्रण रेखा' (Actual Line of Control) से 20 किलोमीटर अपनी ओर हट जाएँगी। सेना का हटना एक दिसम्बर से प्रारम्भ होगा। (2) चीनी सेनाओं के हटने से जो क्षेत्र खाली होगा उसमें चीन सरकार अपनी अर्सेनिक चौकियाँ कायम करेगी। चीन की ओर से भारत सरकार को इन शर्तों को मान लेने के लिए कहा गया कि वह अपनी सेनाओं को भी 7 नवम्बर, 1959 की रेखा से 20 किलोमीटर अपने ही क्षेत्र में ओर हटा ले। विपरीत

परिस्थितियों में भारत ने बिना स्वीकारोक्ति के चीन की एकपक्षीय युद्ध-विराम घोषणा को मान लिया, किन्तु द्वि-भूवीय योजना को अस्वीकृत करते हुए घोषित किया कि जब तक चीनी सेनाएँ 8 सितम्बर, 1962 की स्थिति तक नहीं लौट जाती तब तक दोनों देशों के बीच कोई बातों सम्भव नहीं है। 8 सितम्बर, 1962 को यह रेखा यह थी जिनके उत्तर में चीनी सेनाएँ आक्रमण से पहले स्थित थी जबकि चीन द्वारा बनाई गई। 7 नवम्बर, 1959 की वास्तविक नियन्त्रण रेखा यह थी जहाँ तक आक्रमण के बाद भी चीनी फौजें नहीं पहुँच पाई थी।

चीन के आक्रमण ने भारत की युद्ध-निरपेक्ष नीति के विरुद्ध आलोचनाओं को प्रोत्साहित किया, किन्तु श्री नेहरू ने पुनः इस नीति में गहरी आस्था प्रकट की। अवश्य ही अब भारत की विदेश नीति में वयार्थवाद की ओर झुकाव शुरू हुआ। दिसम्बर, 1962 में श्रीलंका, बर्मा, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, मिस्र और धाना ने भारत-चीन बातों के लिए कोलम्बो-सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें यह निष्कर्ष किया गया कि सम्मेलन के प्रतिनिधि भारत और चीन जाकर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा दोनों देशों के संपर्क को समाप्त करने का प्रयत्न करें। श्रीमती भण्डारनायक के स्वयं कोलम्बो प्रस्ताव लेकर पीकिंग और नई दिल्ली गईं। 29 जनवरी, 1963 को ये प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए गए जिसके मूल तत्व ये थे—

(1) युद्ध-विराम का समय भारत-चीन विवाद के शान्तिपूर्ण हल के लिए उपयुक्त है; (2) चीन पश्चिमी क्षेत्र में अभी अपनी सैनिक-चौकियाँ 20 किलोमीटर हटा लें; (3) भारत अपनी वर्तमान सैनिक स्थिति बरकरार रखे, (4) विवाद का अन्तिम हल होने तक चीन द्वारा सखी किया गया क्षेत्र असैनिक रहे जिसकी निगरानी दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त गैर-सैनिक चौकियाँ करें; (5) पूर्वी तथा क्षेत्र में दोनों सरकारों द्वारा मान्य वास्तविक नियन्त्रण रेखा युद्ध-विराम रेखा का रूप ले, शेष क्षेत्रों के बारे में दोनों देश भावी वार्ताओं में निर्णय करें, (6) मध्यवर्ती क्षेत्र का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से किया जाए। कोलम्बो प्रस्तावों का वास्तविक उद्देश्य भारत और चीन के बीच प्रतिरोध की स्थिति समाप्त कर वार्तालाप का द्वार खोलना था। चीन ने यह आश्वासन दिया कि वह कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगा। स्पष्टीकरण के बाद भारत ने प्रस्तावों पर विधिवत अपनी सहमति दे दी। तब चीन ने कुछ ऐसी बातें जोड़ दी कि जिनसे प्रस्ताव व्यवहारतः महत्वहीन हो गया और चीन की अपरोक्ष स्वीकृति भी स्पष्ट हो गई। चीन ने तटस्थ देशों के इन अनुरोध को ठुकरा दिया कि कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाएँ। भारत-चीन विवाद के प्रतिरोध को दूर करने के लिए 3 अक्टूबर, 1963 को मिस्र के राष्ट्रपति नसिर ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किन्तु इस प्रस्ताव का भी कोई परिणाम नहीं निकला। मई, 1964 में श्री नेहरू की मृत्यु पर श्री चाऊ-एन-लाई ने अपना शोक सन्देश भेजा जिसमें यह भी कहा गया कि भारत और चीन के विवाद अस्थायी हैं जिनका समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से होना चाहिए।

शास्त्री काल में भारत-चीन सम्बन्ध

(मई, 1964—जनवरी, 1966)

पं. जवाहरलाल नेहरू के बाद 10 जनवरी, 1966 तक लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधान मन्त्री रहे। इस काल में भी भारत और चीन के सम्बन्धों में कोई सुधार न आ सका। 1965 के भारत-पाक युद्ध में चीन ने पुनः अपना शत्रुतापूर्ण रवैया प्रदर्शित किया। चीन ने पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया और भारत को आक्रामक घोषित किया। घमकी द्वारा भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध से विमुख करने का खेल भी खेला गया। 16 सितम्बर को चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि—“तीन दिन के भीतर भारत सिक्किम-चीन सीमा पर गैर-कानूनी डंग से स्थापित 56 सैनिक प्रतिष्ठानों को हटा लें अन्यथा इसका नतीजा बहुत बुरा होगा।” पत्र में यह मांग की गई कि भारत सीमा पर अपने सभी अतिक्रमण तुरन्त बन्द कर दे, अपहृत सीमा-निवासियों तथा पकड़े हुए मवेशियों को लौटा दे अन्यथा गम्भीर परिणामों के लिए भारत सरकार पूरी तरह उत्तरदायी रहेगी। महाशक्तियों ने अविलम्ब चीन को चेतावनी दी कि वह आग के साथ खिलवाड़ न करे। उधर चीनी अल्टीमेटम के जवाब में 17 दिसम्बर को श्री शास्त्री ने लोकसभा में कहा कि सिक्किम-तिब्बत सीमा पर भारत के अतिक्रमण की बात गलत है और भारतीय प्रदेश पर चीन का दावा हमें स्वीकार नहीं है। चीन की सैनिक शक्ति भारत को अपनी प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा से विचलित नहीं कर सकती। चीन ने सीमा पर सैनिक गतिविधियाँ आरम्भ कर दी। 19 दिसम्बर को अल्टीमेटम की अवधि फिर तीन दिन के लिए बढ़ा दी, किन्तु बड़े पैमाने पर कोई सैनिक कार्यवाही बगने का साहस नहीं किया। 23 सितम्बर को भारत-पाक युद्ध-विराम हो जाने पर पीनिंग रेडियो ने यह नाटकीय घोषणा की कि “भारतीय सैनिक प्रतिष्ठानों को तोड़कर चीनी सैनिक अपनी सीमा में वापस लौट गए हैं।”

इन्दिरा काल में भारत-चीन सम्बन्ध (जनवरी 1966—मार्च 1977)

भारत-पाक युद्ध में विजय से भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और चीन कुछ समय तक सीमा पर विशेष गड़बड़ी करने से रुका रहा। सितम्बर व अक्टूबर 1967 में चीन ने नायू-ला के भारतीय प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भारी हानि उठाकर पीछे हटना पड़ा। 2 अक्टूबर, 1967 को चीनियों ने चीना की भारतीय चौकी पर अचानक हमला किया, किन्तु फिर गहरी क्षति उठाकर अपने नापाक दरादों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। विदेशों की राजधानियों में दोनों देशों के राजदूतों का सम्पर्क बढ़ने लगा। फिर भी चीन की ओर से सम्बन्ध सुधार के कोई ठोस प्रयत्न दृष्टिगोचर नहीं हुए। 4 अगस्त, 1971 को राज्यसभा में भारतीय विदेश मन्त्री सरदार स्वर्णसिंह ने कहा—“भारत चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार का स्वागत करना है, लेकिन जब तक चीन की ओर से उचित प्रत्युत्तर नहीं मिलता, हम प्रवेने कुछ नहीं कर सकते।” सितम्बर, 1971 में संयुक्त राष्ट्रमण्डल में चीन के प्रवेश की बात उठी और भारत ने चीन की सदस्यता का पूर्ण समर्थन दिया।

दोनों देशों के बीच राजदूतों को नियुक्त करने की बात भी उठी और दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध निड़ गया जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में पुनः तनाव उत्पन्न हो गया। बंगला देश के मुक्ति-ग्रान्दोलन में भारत का सहयोग चीन को अच्छा नहीं लगा। चीन ने भारत के सहयोग को पाकिस्तान के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप बनाया। अगस्त, 1971 को भारत-मोवियन सन्धि ने चीन को और भड़का दिया। दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान सुरक्षा परिषद् की बहसों में चीनी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का साथ देने में कोई कसर नहीं रखी और भारत को आक्रमणकारी धोषित कर दिया।

चीन के प्रसार-साधन भारत के विरुद्ध शत्रुनापूर्ण प्रचार करते रहे। चीन सरकार ने 29 अप्रैल, 1975 को एक वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि भारतीय संध में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त होना 'मर्यादित अधिग्रहण' है। भारत सरकार ने इसे अपने आन्तरिक मामले में चीन का हस्तक्षेप बताया। चीन बराबर यह दावा करता रहा कि भारत अपने पड़ोसियों के प्रति 'आधिपत्य और विस्तारवादी आकांक्षाएँ' रखता है और चाहता है कि वह सोवियत संघ के समर्थन से एक 'उप-महा-देश' बन जाए। चीन के इस मिथ्या प्रचार के बावजूद भारत ने किसी प्रकार का कोई प्रचार आन्दोलन नहीं छोड़ा। भारत सरकार चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए सुसंगत नीति का अनुसरण करती रही। वर्ष 1976 भारत और चीन के बीच सम्बन्ध सुधार का सन्देश लेकर आया। अप्रैल, 1976 में भारत ने चीन में अपना राजदूत नियुक्त किया और सितम्बर, 1976 में चीनी राजदूत ने दिल्ली में अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किए। अक्टूबर-नवम्बर, 1976 में चीन की बेंडमिण्टन टीम की भारत-यात्रा और दिसम्बर, 1976 में एक गैर-सरकारी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की चीन-यात्रा से दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सम्बन्धों की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।

जनता शासन-काल में भारत-चीन सम्बन्ध (अप्रैल 1966-1979)

भारत का एक गैर-सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल अप्रैल, 1977 में 'कॅण्टन सिंग फेरि' में सम्मिलित हुआ। करीब 15 वर्ष बाद दोनों देशों के बीच सीधा व्यापार फिर से आरम्भ होने से दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सुविधाओं और मालवाहक जहाजों के आवागमन को प्रोत्साहन मिला। कृषि, खनन, पन-विज्ञान, चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य और खेल-कूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी आदान-प्रदान किया गया। फरवरी, 1978 में चीन के एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने भारत की यात्रा की। मार्च, 1978 में चीन के एक गैर-सरकारी सद्भावना प्रतिनिधि मण्डल ने भारत की यात्रा की। विदेशमन्त्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने 12 से 18 फरवरी, 1979 तक चीन की यात्रा की। विदेशमन्त्री ने यह स्पष्ट बताया कि भारत को पाकिस्तान और चीन के बीच सामान्य द्विपक्षीय सम्बन्धों पर यद्यपि कोई आपत्ति नहीं है लेकिन भारत-चीन सम्बन्धों के सुधार की सम्भावनाओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर उनके पारस्परिक सम्बन्धों से भारत के बंध हितों पर यदि

कोई उनका बुरा अमर पड़ता हो। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि चीन सरकार ने कश्मीर के प्रश्न पर जो रुख अपनाया है वह छठे दशाब्द के मध्य उनके अपने ही रवैये के विपरीत है तथा उसमें चीन-भारत सम्बन्धों में एक अनिश्चित और अनावश्यक पेचीदमी आ गई है। चीनी नेताओं के साथ अपनी बातचीत में विदेशमन्त्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत-चीन सीमा प्रश्न का सन्तोषजनक समाधान, पारस्परिक विश्वास पुनः जमाने के लिए और चीन-भारत सम्बन्धों के बानावरण को पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पीकिंग में अपनी बातचीत पूरी करने के बाद विदेशमन्त्री शाऊचो गए जहाँ 17 फरवरी को उन्हें वियतनाम पर चीनी आक्रमण की खबर मिली। उन्होंने तत्काल अपनी शेष यात्रा रद्द कर दी और तुरन्त भारत लौट आए। भारत सरकार ने वियतनाम पर चीनी आक्रमण का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया और कहा कि चीनी फौजों को वापस हटना चाहिए। कुल मिलाकर जनता शासनकाल में भारत-चीन सम्बन्ध यथापूर्व बने रहे।

श्रीमती गांधी के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद
भारत-चीन सम्बन्ध (फरवरी 1982 तक)

चीन ने नवम्बर-दिसम्बर, 1979 में नई दिल्ली में आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी बड़े पैमाने पर भाग लिया विभिन्न क्षेत्रों के अनेक भारतीय विशेषज्ञों ने समुक्त राष्ट्रसंघ के अभिवर्णों के तत्त्वावधान में चीन की यात्रा की। चीन के कई शिष्ट-मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने भारत आए। श्री गोन्याल्वेज, मन्त्रि (पूर्व) जब जून, 1980 के मध्य में पीकिंग की यात्रा पर गए तो भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की कार्यवाही सिमी दूसरे देश के साथ अपनी मिश्रता की कीमत पर नहीं की जाएगी। वर्ष 1980 और 1981 के दौरान भारत और चीन के बीच सम्पर्क सूखे का विकास होता रहा। 1981 में सीमा विवाद मुलभाने की दिशा में नए प्रयास शुरू हुए और लगभग दो दशकों के बाद पीकिंग में 10 दिसम्बर में 15 दिसम्बर, 1981 तक चीन और भारत के प्रतिनिधि एक-दूसरे के आमने-सामने बैठकर दोनों देशों के बीच के सीमा विवादों को मुलभाने के प्रयास में जुटे रहे। बार्ता के अनेक दौर चढ़ने की सम्भावना है। एक बार दोनों देशों के सामान्य सम्बन्ध बन जाएँ तो इसका प्रभाव विश्व की राजनीति पर अवश्य होगा और नताव का बानावरण बहुत कम हो जाएगा। 22 फरवरी, 1982 में भारत में 44 विकासशील देशों का जो तीस दिवसीय सम्मेलन आरम्भ हुआ उसमें चीन के उपमन्त्री ने भी भाग लिया।

भारत और श्रीलंका

भारत और श्रीलंका के सम्बन्ध उत्तार-चढ़ाव के रहे हैं, तथापि कुल मिलाकर दोनों देशों की मैत्री में कृत्रिम टूट है और पारस्परिक विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से

सुनझाया गया है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत ने श्रीलंका के आर्थिक विस्तार में सहायता दी थी। 1955 के बाण्डुंग-सम्मेलन में दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ सहयोग किया। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के संदर्भ में श्रीलंका ने निष्पक्ष नीति का अवलम्बन न कर भारतीय भावनाओं को ठेस पहुँचाई, तथापि प्रधानमंत्री श्रीमती भण्डारनायके ने तटस्थ देशों वर कोलम्बो सम्मेलन आयोजित किया और सम्मेलन द्वारा पारित कोलम्बो-प्रस्तावों के सम्बन्ध में पीकिंग तथा दिल्ली की यात्राएँ की।

भारत की आजादी के पूर्व 1939 से ही दोनों देशों के बीच राज्य-विहीन नागरिकों से सम्बन्धित जो विवाद था वह लम्बे प्रसे तक चला रहा, किन्तु अक्टूबर, 1964 में शास्त्री-भण्डारनायके समझौते द्वारा उसे सुलझा लिया गया। सभी राज्य-विहीन नागरिकों को भारत या श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करने के आवेदन देने में लिए कहा गया। 1965 में दोनों देश अधिक निकट आ गए जब श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री सेतानायक ने भारत के न्यायोचित पक्ष का समर्थन किया और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने तथा कोलम्बो-प्रस्तावों को न मानने के लिए उसकी निन्दा की। 1970 में नेतृत्व पुनः श्रीमती भण्डारनायके के हाथ में आया। मई, 1971 में उनकी सरकार को उग्रवादी वामपन्थियों के व्यापक विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसे दबाने के लिए भारत ने आसनों की सहायता दी। श्रीमती गाँधी ने अप्रैल, 1972 में श्रीलंका की यात्रा की। जनवरी, 1973 में श्रीमती भण्डारनायके भारत आई। भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच लगभग 200 एकड़ के कच्चातिलू नामक छोटे-से द्वीप पर आधिपत्य सम्बन्धी विवाद भी 28 जून, 1974 के समझौते द्वारा निपटा लिया गया। इस द्वीप पर नागफिरा के अतिरिक्त और कुछ नहीं उगता। भारत ने एक महान् पड़ोसी देश की परम्परा का निर्वाह करते हुए कच्चातिलू को श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में मान लिया। अप्रैल, 1976 में दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा सम्बन्धी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वीकार किया कि प्रत्येक देश के तट के 200 मील तक का समुद्री क्षेत्र उसका अधिक क्षेत्र होगा और जहाँ दोनों के बीच की दूरी 200 मील से कम होगी वहाँ दूसरे देश की मध्यस्थ रेखा सीमा रेखा होगी। अगस्त, 1976 में भारत के प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री ने कोलम्बो की यात्रा की। मार्च, 1977 में भण्डारनायके के पतन के बाद श्री जयवर्धन श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच 1977 में ही एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने सामूहिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुओं तथा मध्यवर्ती साज-सामान की खरीद के लिए श्रीलंका को 7 करोड़ रुपये का ऋण दिया। श्रीलंका के संशोधित सुविधान के अन्तर्गत श्री जे. आर. जयवर्धन की प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति बनाए जाने के अवसर पर आयोजित समारोहों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 से 6 जनवरी, 1978 तक भारत के गृहमंत्री ने श्रीलंका की यात्रा की। अक्टूबर, 1978 में राष्ट्रपति जयवर्धन की यात्रा और फरवरी, 1979 में

श्री मोरारजी देसाई की श्रीलंका यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में विद्यमान सौहार्द्रता परिलक्षित हुई। दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच अब कोई समस्या नहीं है। जनवरी, 1980 में श्रीमती गाँधी के पुनः सत्तास्थ होने के बाद से दोनों देशों के सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हुए हैं।

भारत और नेपाल

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से तो दोनों देश अति निकट हैं, साथ ही आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के कारण भी दोनों में मैत्री स्वाभाविक है। 31 जुलाई, 1950 की सन्धि द्वारा दोनों देश निश्चय कर चुके थे कि वे शान्ति और मैत्री की नीति का अनुसरण करेंगे। दोनों में एक व्यापारिक सन्धि भी सम्पन्न हुई जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि नेपाल अपना विदेशी व्यापार भारतीय क्षेत्र से होकर मुचरू रूप से कर सकेगा। नेपाल में कुछ भारत विरोधी तत्त्व पहले ही विद्यमान थे। साम्यवादी चीन भी अपने प्रभाव विस्तार के लिए भीतर ही भीतर नेपाल में भारत-विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन दे रहा था। अतः नेपाल में यह विचार बल पकड़ने लगा कि नेपाल को भारत का और चीन के मध्य एक अवरोधक (बफर) राज्य की भूमिका निभानी चाहिए। भारत ने नेपाली राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारत नेपाल की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के लिए सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करता रहा। सन् 1956 में टकाप्रसाद आचार्य नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उनका झुकाव चीन की ओर था, अतः नेपाल में भारत-विरोधी वातावरण तैयार करने में उनका प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग रहा। 1957 में डॉ. के. आई. प्रधानमंत्री बने और 1959 में बी. पी. कोइराला। इन दोनों ही के प्रधान मन्त्रित्वकाल में भारत-नेपाल सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हो सका। प्रधानमंत्री कोइराला ने चीन के साथ एवरेस्ट पर्वत शिखर के बारे में ऐसा समझौता किया जो नेपाल सरकार का भारत के साथ विश्वासघात था। कोइराला-मन्त्रिमण्डल के पतन के बाद भी 1961 तक दोनों देशों के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे। भारत के विरोध के बावजूद राजा महेन्द्र ने काठमाण्डू-ल्हासा सड़क मार्ग बनाने के सम्बन्ध में चीन से समझौता किया। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के प्रति भी नेपाल ने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार साम्यवादी चीन के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से सहानुभूति प्रकट की।

1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद श्री शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नेपाल की यात्रा की और दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ। राजा महेन्द्र भारत आए और राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन् नेपाल गए। एप्रिल, 1964 में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत ने 9 करोड़ रुपये की लागत में नेपाल के लिए एक 128 मील लम्बी सड़क बनाने का निर्णय किया। काठमाण्डू से भारतीय सीमा रक्मौल को जोड़ने वाली एक अन्य सड़क योजना भी भारत ने अपने हाथ में ली। 1965 में श्री शास्त्री ने कोसी-योजना के पश्चिमी-नहर कार्य का उद्घाटन किया। योजना का उद्देश्य नेपाल को बाढ़ की रक्षित से बचाना

और बिजली तथा सिंचाई से लाभ पहुँचाना था। दिसम्बर, 1965 में नेपाल नरेश ने भारत-याना की और एक संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा स्वीकार किया कि भारत की सहायता से नेपाल में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति सन्तोषजनक है।

श्री शास्त्री के बाद श्रीमती गांधी ने भी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने की नीति को आगे बढ़ाया। अक्टूबर, 1971 में दोनों देशों के बीच कोभी तथा गण्डक परियोजनाओं के निर्माण के लिए समझौता हुआ। जनवरी, 1972 में राजा महेन्द्र की मृत्यु हो गई और उनके बाद राजा बीरेन्द्रशाह गद्दी पर बैठे। भारत नेपाल के विकास कार्यक्रमों में रवि लेता रहा। राजा बीरेन्द्र का रवैया भारतीय उदारता के बावजूद कई दृष्टियों से घबराते वाला था। 1973 में उन्होंने नई भौगोलिक स्थिति की घोषणा करते हुए कहा कि नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है। सितम्बर, 1974 में राजा बीरेन्द्र ने सिक्किम को भारत में सह-राज्य का दर्जा दिए जाने का खुल्लमखुल्ला विरोध किया। काठमाण्डू स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत के विरुद्ध बुलेटिन निकाले गए। नेपाल सरकार की चुप्पी ने चीनी दूतावास द्वारा भारत-विरोधी प्रचार को बढ़ावा दिया। नेपाल के भारतीय रवय को असुरक्षित महसूस करने लगे। इन घटनाओं को भारत सरकार ने अत्यन्त गम्भीरता से लिया। नेपाल सरकार ने समझ लिया कि भारत के सहयोग और समर्थन के बिना गाड़ी चलाना कठिन है। नवम्बर, 1974 के लगभग नेपाली पत्र 'मदरलैण्ड' ने कहा कि विश्व के 'लैण्ड लाकड' देशों की जो सुविधाएँ प्राप्त हैं वही नेपाल को भी मिलनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्रों के अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री चट्वाण ने नेपाली प्रधानमन्त्री श्री रिजाल को स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत नेपाल को हर प्रकार से सहायता देने को तैयार है, किन्तु संचार एवं बन्दरगाह सुविधाओं की अधिकार के रूप में नहीं माँगा जाना चाहिए। नेपाल को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह इस महाद्वीप की रक्षा-व्यवस्था का एक अंग है। भारत के कड़े रुख को देखकर नेपाल के महाराजा ने अग्रयक्ष और कूटनीतिक क्षेत्रों के माध्यम से भारत से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का आग्रह किया। 1975 में दोनों देशों के बीच सम्बन्ध मित्रतापूर्ण बने रहे। नेपाल नरेश भारत आए।

वर्ष 1976 में दोनों देशों के सम्बन्धों की दिशा में काफी ठोस कार्य हुआ। राजनीतिक और सरकारी स्तर पर कई यात्राएँ हुईं जिससे दोनों सरकारों के बीच लगातार वार्ता का अवसर प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि नेपाल के जो राष्ट्रीय भारत के सरक्षित, प्रतिबन्धित क्षेत्रों का दौरा करना चाहेंगे उन्हें दूगरे विदेशी राष्ट्रों के समक्ष ही माना जाएगा और इस प्रकार उन्हें भी इन उद्देश्य के लिए परिपत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा। 1976-77 में नेपाल की विकास-योजनाओं के सहायता अनुदान के रूप में बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। अप्रैल, 1977 में नेपाल नरेश की भारत यात्रा और उसके बाद जुलाई, 1977 में भारत के विदेशमन्त्री की नेपाल यात्रा और फिर दिसम्बर, 1977 में भारत के प्रधानमन्त्री की नेपाल यात्रा से आपसी आस्था और विश्वास की भावना के साथ इस प्रकार के सम्बन्ध विस्तित

करने में सहायता मिली। भारत-नेपाल के विकास कार्यक्रमों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देता रहा। मार्च, 1978 में नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन के लिए अलग-अलग सन्धियाँ तथा अनधिकृत व्यापार पर नियन्त्रण के लिए सहयोग के सम्बन्ध में अन्तर-सरकारी करार के सम्पन्न होने से भारत और नेपाल के बीच परस्पर लाभदायक सहयोग को सम्बर्धित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। 1979-80 के दौरान भारत और नेपाल दोनों ही देश अपनी-अपनी आन्तरिक घटनाओं में व्यस्त रहे। अपनी समस्याओं के बावजूद सितम्बर, 1979 में नेपाल के महाराजाधिराज भारत की यात्रा पर आए। इस बात पर सहमति हुई कि कर्नाली, पंचेश्वर और राप्ती जैसी कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय पन-विजली परियोजनाओं आदि का अध्ययन शीघ्रता से पूरा किया जाए।

वर्ष 1980-81 में भारत की तरह नेपाल में भी महत्वपूर्ण आन्तरिक परिवर्तन हुए। सरकार का स्वरूप निश्चित करने के लिए मत-संग्रह के बाद यानी इस बात का फैसला कर लेने के बाद कि वहाँ दलविहीन पंचायती व्यवस्था चलनी रहे अथवा उसकी जगह बहु-दलीय व्यवस्था अपनायी जाए, संविधान में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन की दिशा में कार्यवाही की गई। दोनों ही देशों के सम्बन्धों को एक ऐसा सुदृढ़ आधार देने के उद्देश्य से गम्भीर रूप से प्रयत्न किए गए जो समानता, पारस्परिक विश्वास और पारस्परिकता पर आधारित हो। द्विपक्षीय सहयोग की लम्बी परम्परा निरन्तर चलती रही खासतौर पर जल-ससाधनों के विकास के क्षेत्र में जैसा कि कर्नाली और पंचेश्वर योजनाओं से प्रकट होता है।

भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्धों पर भारत

सरकार की रिपोर्ट 1980-81

वर्ष 1980-81 के दौरान पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो सम्बन्ध रहे उन पर भारत सरकार की 1980-81 वार्षिक रिपोर्ट से अच्छा प्रकाश पड़ता है। साथ ही हमें इन सम्बन्धों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सैकितिक ज्ञान प्राप्त होता है। रिपोर्ट इस प्रकार है—

भारत और अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के साथ भारत के निवट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है और वहाँ जो घटनाएँ घटीं उनसे उसका गम्भीर रूप से चिन्तित हो जाना स्वाभाविक था। अपने इस पुराने मित्र और पड़ोसी देश की सुरक्षा, स्वतन्त्रता, प्रमुक्तता, प्रादेशिक सम्बन्धना और उनकी गुट-निरपेक्ष स्थिति में वह गहरी दिलचस्पी रखता है।

स्थिति को सामान्य करने के उद्देश्य से, विदेश मन्त्रालय के अपर सचिव श्री एस. के. सिंह काबुल गए और वहाँ उन्होंने काबुल के नेताओं से बातचीत की। विदेश मन्त्री ने न्यूयॉर्क में, अफगानिस्तान के विदेश मन्त्री से बई बार बातचीत की। भारत ने इस समस्या के सम्बन्ध में दूसरे देशों के नेताओं से भी विचार-विमर्श किया।

अफगानिस्तान के सम्बन्ध में भारत की नीति इन सिद्धान्तों पर आधारित है कि (i) किसी एक देश के मामले में किसी दूसरे देश को सशस्त्र शक्ति के प्रयोग से हस्तक्षेप अथवा दखलन्दगी नहीं करनी चाहिए, (ii) बाहरी हस्तक्षेप अथवा तोड़-फोड़ के माध्यम से वर्तमान सरकार को अस्थिर बनाने के प्रयत्न नहीं किए जाने चाहिए, और (iii) प्रतिशय जस्त्र भँगाकर या भेजकर, बड़ी शक्तियों के प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ के द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र को अस्थिर नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत का यह दृढ़ मत है कि इस मिलसिले में प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि तनाव को बढ़ने से रोका जाए और राजनीतिक तथा राजनयिक साधनों से समाधान की दिशा में अनवरत प्रयास किया जाए।

भारत और बंगलादेश

भारत बंगलादेश के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने की दिशा में गिरन्तर प्रयत्न करता रहा। दोनों ओर से मन्त्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित यात्राओं के आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों सरकारों के बीच रचनात्मक वार्ता चलती रही। इस सन्दर्भ में बंगलादेश के राष्ट्रपति और भारत की प्रधानमन्त्री की बैठक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात सितम्बर, 1980 में नई दिल्ली में हुई जबकि बंगलादेश के राष्ट्रपति, राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। विदेशमन्त्री ने 16 से 18 अगस्त, 1980 तक ढाका की यात्रा की जबकि उन्हें बंगलादेश की सरकार के साथ भू-सीमा, जल-सीमा, सीमा पर अरबध आवागमन तथा रेल पारगमन की सुविधा जैसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय प्रश्नों पर व्यापक विचार-विमर्श करने का मौका मिला। इनमें से बहुत से प्रश्नों का यद्यपि कोई तात्कालिक समाधान तो नहीं मिल सका लेकिन अनेक द्विपक्षीय मसलों पर हम आगे बढ़ सकें और घागे की कार्यवाही के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया।

1974 के भारत-बंगलादेश भूमि-सीमा करार को क्रियान्वित करने की दिशा में तेजी लाने के सिलसिले में दिसम्बर, 1980 में नई दिल्ली में अधिकारी स्तर की बातचीत हुई। सीमा को अंकित करने का काम 1981-82 के क्षेत्र मौयम से पूर्व पूरा कर लेने के इरादे से विशेष कार्यक्रम बनाए गए। जल-सीमा को अंकित करने के लिए अधिकारी स्तर की बातचीत दिसम्बर, 1980 में ढाका में पुनः शुरू हुई। इससे पहले 1974 तथा 1978 के बीच इस सिलसिले में बातचीत के छह दौर हो चुके हैं।

रेल-पारगमन सुविधा प्रदान करने के बंगलादेश के अनुरोध पर सिद्धान्त रूप में सहमत हो जाने के बाद इस सिलसिले में आगे की कार्यवाही के लिए अक्टूबर, 1980 में भारत से एक प्रतिनिधिमण्डल ढाका गया और वहाँ उसने बंगलादेश होते हुए पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच माल पारगमन यातायात के प्रबन्धकों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की। एक तकनीकी उप-दल ने रेल गोदामों के निर्माण के

लिए सम्भावित स्थलों का निरीक्षण किया जिसका लक्ष्य बंगलादेश की रेल व्यवस्था को त्रिपुरा में अगरतला शहर से जोड़ना है। इस यात्रा में पारगमन सुविधाएँ स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक कल्याण कार्यों के क्षेत्र में भारत और बंगलादेश ने पिछले चार वर्ष से चली आ रही तदर्थ स्थिति को सतम करने का निश्चय लिया जिसके फलस्वरूप 30 दिसम्बर, 1980 को एक सांस्कृतिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए जिसका उद्देश्य दोनों देशों से नियमित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करना है। यह प्रोटोकॉल दोनों देशों के बीच 30 दिसम्बर, 1972 को सम्पन्न सांस्कृतिक सहयोग की रूपरेखा के अन्तर्गत किया गया है।

अक्टूबर, 1980 में भारत के वाणिज्य मन्त्री श्री प्रणवकुमार मुखर्जी ने ढाका की यात्रा की जिसके परिणामस्वरूप भारत और बंगलादेश के बीच वाणिज्यिक आदान-प्रदान को एक नया प्रोत्साहन मिला। दोनों देशों के बीच एक नए व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए जो प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए बंध होगा। इसी यात्रा के दौरान भारत और बंगलादेश के बीच सद्भाव ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार भारत को गीले नीले चमड़े (वेट ब्लू लेदर) के निर्यात की 25 करोड़ टका के बराबर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 40 करोड़ टका कर दिया गया। इसी ज्ञापन में भारत ने एक लाख टन की मात्रा तक यूरिया उर्वरक सौदेबाना स्वीकार किया और कुछ वर्षों की औषधियों, मिट्टी के तेल, जामदानी साड़ी और हाथकरघे की वस्तुओं के आयात के प्रश्न पर विचार करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। बंगलादेश ने 1980-81 वर्ष के दौरान स्टीम कोयला की सप्लाई के लिए अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त उसने लौह-पिण्ड, जी. आई. शीट, गेहूँ के बीजों के आयात में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई।

जैसा कि फरक्का पर गंगा के पानी के बँटवारे और उसके प्रवाह को बढ़ाने से सम्बद्ध करार (1977) में परिकल्पित है, इसमें निहित प्रवन्धों के अनुरूप काम, उसके प्रभाव क्रियान्वयन और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए पहली समीक्षा पर 5 नवम्बर, 1980 को ढाका में हस्ताक्षर किए गए। जनवरी, 1981 को दिल्ली में मन्त्री-स्तर की एक और बैठक समीक्षा करने के लिए हुई। दोनों पक्षों ने इस समीक्षा पर अपनी-अपनी रिपोर्टों का आदान-प्रदान किया जो अल्पकालिक बँटवारे के प्रवन्धों से और फरक्का पर गंगा के प्रवाह की सुश्की के मौसम में बढ़ाने से सम्बद्ध प्रावधान दोनों के बारे में थीं। इस करार में भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग से कहा गया कि प्रवाह बढ़ाने से सम्बद्ध योजना पर वह अपनी मिफारिजें तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर दोनों सरकारों को प्रस्तुत कर दें। संयुक्त नदी आयोग इस अवधि में भारत और बंगला देश द्वारा प्रस्तुत उनकी अपनी-अपनी योजनाओं पर विचार करने का काम भी शुरू नहीं कर सका जिसके कारण, भारतीय पक्ष ने पुनः विचार के लिए हुई बैठक में प्रस्तुत किए। इनके विपरीत, करार में जिन अन्य-

कालिक वेंटवारे के प्रबन्धों की परिकल्पना की गई थी, उन पर पूरी ईमानदारी के साथ और पूर्ण रूप से अमल किया गया।

नवोदिन न्यूमूर द्वीप पर भारत के अधिकार पर बंगलादेश ने आपत्ति की। भारत ने बंगलादेश को इस द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आंकड़े दिए और इस सिलसिले में बंगलादेश के साथ आगे बातचीत होनी है जिसमें इस सवाल का प्रयत्न किया जाएगा कि इस पर भारत के उचित अधिकार के सम्बन्ध में अगर कुछ गंका-सन्देह हो तो उसे दूर किया जाए।

भारत और भूटान

समीक्षाधीन वर्ष (1980-81) के दौरान भूटान और भारत के बीच कई उच्चस्तरीय यात्राएँ हुईं जो भूटान के साथ भारत के निकट सम्बन्धों का प्रमाण है। भूटान के विदेशमन्त्री ने अगस्त, 1980 में भारत की यात्रा की। न्यूपॉर्क में उनसे मेट होने पर विदेशमन्त्री ने दोनों देशों के समान हित के मामलों पर और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उनसे विचार-विनिमय किया। भूटान नरेश ने 9 से 11 जनवरी, 1981 तक भारत की यात्रा की और उनकी इस यात्रा से भारत और भूटान के बीच परस्पर विश्वास, सद्भाव, पारस्परिक निमंरता और हितों की पारस्परिकता के विशिष्ट सम्बन्धों की पुनः पुष्टि हुई।

इन यात्राओं के अतिरिक्त दोनों देशों के कई सरकारी प्रतिनिधिमण्डल और अधिकारी भी एक-दूसरे के पहाँ आए गए। और उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय और दूसरे प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया।

भारत भूटान को आर्थिक और तकनीकी सहायता बराबर देता रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि भारतीय आर्थिक और तकनीकी सहायता से भूटान द्वारा किया-गिरा की जा रही है, भूटान ने शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में तथा सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की दिशा में तथा सड़क पुल, संचार एवं दूर-संचार, विद्युत आदि जैसी आधुनिक संरचना जैसी सुविधाओं का निर्माण करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस समय भूटान की पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारत की भागीदारी के आधार के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

पहले की तरह ही इस वर्ष भी भूटान को प्रतिनियुक्तिके आधार पर भारतीय विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की सेवाएँ प्रदान की गईं। भारत भूटान के विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों को भारत में उच्चतर अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देता रहा।

भारत और बर्मा

राष्ट्रपति यू-ने-विन ने अपने विदेशमन्त्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 20 से 22 नवम्बर तक भारत की राजकीय यात्रा की। बर्मा के नेताओं ने भारतीय नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच आपसी रुचि

के विभिन्न मसलो पर विचार-विमर्श हुआ। इस मौके पर आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में भी विचार किया गया।

बर्मा के राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर, बर्मा के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ऊ-नू 29 जुलाई को भारत से रगून के लिए रवाना हो गए।

रगून में भारत के राजदूत ने बौद्ध धर्म की पुस्तकें और महात्मा गांधी की कृतियों के सकलन बर्मा के उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक को भेंट किए।

भारत और ईरान

ईरान के साथ भारत के सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण बने रहे हैं। दोनों ने परस्पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को सराहा है। ईरान के नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की क्षमता की ओर अपनी अधिकाधिक सजगता व्यक्त की और जून, 1980 में ईरान के वाणिज्यमन्त्री श्री रजा सदर की नई दिल्ली यात्रा के दौरान हुई बातचीत के बाद, यह तय किया गया कि व्यापार, उद्योग, जहाजरानी, परिवहन और रेल, कृषि, योजना और विज्ञान तथा औद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत और ईरान के बीच सहयोग बढ़ाया जाए। भारत के इजीनियरी निर्यात सर्वेक्षण परिषद् के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भी ईरान की यात्रा की और उसकी यात्रा के बाद सितम्बर में भारतीय इजीनियरी उद्योग एसोसियेशन का एक प्रतिनिधिमण्डल भी वहाँ गया। लेकिन दुर्भाग्य से ईरान और ईराक के बीच लड़ाई छिड़ जाने से भारत और ईरान के बीच आर्थिक सहयोग के विकास के मार्ग में व्यवधान उपस्थित हो गया। इस लड़ाई के खतम हो जाने के बाद भारत और ईरान के बीच सहयोग में प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रत्याशा की जा सकती है।

वित्तमन्त्री श्री आर. वेंकटरमन ने सितम्बर, 1980 में प्रधानमन्त्री के विशेष दूत के रूप में ईरान की यात्रा की। वहाँ उन्होंने यह पाया कि 'ओपेक' से रियायती शर्तों के सिलसिले में विभिन्न देशों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें भारतीय स्थिति के प्रति भारत के दृष्टिकोण को ईरान के नेता पूरी तरह से समझते हैं।

ईरान के उद्योग एवं खान उपमन्त्री, डॉ. सैयद अली सत्तारी पोर के नेतृत्व में ईरान के आर्थिक और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के एक शिष्टमण्डल ने फरवरी, 1981 में नई दिल्ली में भारत के इजीनियरी उद्योग एसोसियेशन द्वारा आयोजित इजीनियरी व्यापार मेले का दौरा किया। ईरान तेल सप्लाई का एक विश्वमनीय स्रोत बना रहा है।

भारत और मालदीव

मालदीव के साथ भारत के सम्बन्धों में राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। माले में भारत के प्रतिनिधित्व का स्तर उठा कर रिहायशी राजदूत का बना दिया गया और उस पर राजदूत की नियुक्ति की गई है।

नवम्बर, 1980 में भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार करार

के सिलसिले में बातचीत हुई। उम्मीद है कि जल्दी ही एक करार पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। आशा की जाती है कि इस करार के सम्पन्न हो जाने के बाद भारत और मालदीव के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हो जाएगी।

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने मालदीव में ड्रलून हवाई अड्डे के विस्तार की परियोजना की सविदा प्राप्ति पूरी कर ली है। हवाई पट्टी बन कर पहले ही तैयार हो चुकी है और उम्मीद की जाती है कि इसकी इमारत और दूसरी छोटी-छोटी इमारतें भी 1981 के मध्य तक पूरी हो जाएँगी।

भारत और नेपाल

भारत नेपाल के साथ अपने बहुमुखी सम्बन्धों को और अधिक विकसित एवं सुदृढ़ करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहा है।

नेपाल के महामहिम नरेश ने मार्च, 1980 में भारत की यात्रा की और इस अवसर पर उनके साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विचार-विमर्श हुआ जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी मामले शामिल थे। इस बातचीत में इस क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया और दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में सभी देशों को तथा बाहरी शक्तियों को भी इस क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बारे में भी महसूस हुई कि परस्पर लाभदायक क्षेत्रों में भारत और नेपाल के सम्बन्धों को विकसित करने की कोशिश की जानी चाहिए तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच पहले से ज्यादा जल्दी-जल्दी परामर्श होने चाहिए।

जुलाई, 1980 में बीरगंज और रक्सौल के बीच एक सूक्ष्म तरंग सम्पर्क का निर्माण करने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस करार के अन्तर्गत नेपाल की सरकार को 12 साल रुपये की तकनीकी और सामग्रीगत सहायता दी जाएगी। इस सम्पर्क की स्थापना हो जाने से नेपाल और भारत के बीच संचार के लिए 36 चैनल उपलब्ध हो जाएँगे।

नेपाल के विदेश सचिव श्री जगदीश शमशेर राणा ने 31 जुलाई से 3 अगस्त, 1980 तक नई दिल्ली की राजकीय यात्रा की। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के सचिवों श्री राणा और विदेश सचिव श्री चार डी साठे के बीच निरन्तर चलने वाले द्विपक्षीय परामर्श के सिलसिले में ही थी और दूसरे क्षेत्रीय घटनाओं पर विचार किया गया जिनमें अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया और हिन्दमहासागर की घटनाएँ भी शामिल थी। दोनों अधिकारियों ने द्विपक्षीय मामलों पर तथा आपसी हित के दूसरे प्रश्नों पर भी विचार विमर्श किया।

अगस्त, 1980 में नेपाल के सिन्धु सचिव की यात्रा के दौरान, भारत ने अपने इस सक्लप पर बल दिया कि जल-संसाधनों का इस प्रकार विकास करने के उद्देश्य से वह नेपाल के साथ पूरा-पूरा सहयोग करेगा जिससे कि दोनों देशों को परस्पर लाभ हो।

भारत-नेपाल की सीमा पर महाकाली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वरी पनविजली परियोजना के सम्बन्ध में अक्तूबर में नेपाली अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद यह तय किया गया कि पंचेश्वर बांध के लिए संयुक्त अन्वेषण काम जितना जल्दी हो सके शुरू हो जाना चाहिए। इस बारे में भी सहमति हुई कि मुख्य करनाली समिति की बैठक भी शीघ्र होनी चाहिए।

भारत नेपाल के विकास कार्यक्रमों के त्रिआन्वयन में सहायता देता रहा है। 1980-81 में नेपाल को भारत की सहायता के रूप में कुल मिला कर लगभग 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इस सहायता का एक बहुत बड़ा भाग वहाँ की उन परियोजनाओं के लिए था जिन पर इस समय काम हो रहा है, जैसे देवी घाट पनविजली परियोजना और पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (मध्य क्षेत्र)। भारत नेपाल में तकनीकी जन-शक्ति संसाधनों के विकास की दिशा में प्रमुख योगदान देता रहा है।

करनाली परियोजना की मुख्य समिति की बैठक काठमांडू में 19 और 20 जनवरी, 1981 को हुई जिसमें नेपाली और भारतीय दोनों पक्ष संयुक्त प्रायोजित और दोनों देशों के मौजूदा सर्वेक्षण के अधीन मुख्य करनाली परियोजना के व्यापक अध्ययन पर सहमत हुए। नेपाली पक्ष ने यह स्वीकार किया कि मुख्य करनाली परियोजना के व्यापक अध्ययन और उसकी विस्तृत परियोजना तैयार करने के निमित्त धन की व्यवस्था करने के लिए वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक से पुरजोर अनुरोध करेगा। भारतीय पक्ष ने यह स्वीकार किया कि वह मुख्य करनाली परियोजना से परस्पर सहमत शर्तों और स्थायी आधार पर विजली लेता रहेगा।

भारत और पाकिस्तान

जनवरी, 1980 में कार्यभार सम्भालने के बाद सरकार निरन्तर पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की जनता को यह आश्वामन दिलाने की कोशिश करती रही है कि वह पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने में हमेशा दिलचस्पी रखनी चाई है और रखती है। फरवरी, 1980 में विदेश सचिव श्री आर. डी. साठे की यह यात्रा और अप्रैल, 1980 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में मरदार स्वर्णसिंह की इस्लामाबाद यात्रा विश्वास पैदा करने के उम उपक्रम का ही एक अंग थी जो भारत समय-समय पर करता आया है। प्रधानमंत्री की मुलाकात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक से लिसवरी में हुई और पाकिस्तान के विदेशमंत्री श्री आगाशाही ने भी जुलाई, 1980 में नई दिल्ली की यात्रा की। भारत को यह आशा है कि इन वार्ताओं के माध्यम से वह दोनों देशों के बीच परस्पर भरोसा और सहभाव बढ़ा सकेगा और सम्बन्धों को तेजी के साथ सामान्य करने के लिए अपेक्षित वातावरण तैयार कर सकेगा।

लेकिन भारत कतिपय ऐसी घटनाओं की ओर से चिन्तित है जिनसे सम्बन्धों को सुधारने के उसके प्रयत्नों को धरना पहुँच सकता है। जनवरी, 1981 में इस्लामी

विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में और उसी महीने इस्लामी शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जिया ने कश्मीर के स्वातंत्र्य की चर्चा करना मुनासिब समझा। इसके पहले 3 अक्टूबर, 1980 को वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भी इसका उल्लेख कर चुके थे। कश्मीर को लेकर भारत-पाक मतभेदों को अन्तर्राष्ट्रीय बनाने के ये प्रयत्न शिमला-समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है और भारत इन्हें सामान्यीकरण की प्रगति के विरुद्ध मनोवृत्ति मानता है। इसी तरह अगस्त, 1980 में मुरादाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर पाकिस्तान के प्राधिकारिक प्रवक्ता ने और वहाँ के सेंसरशुदा अखबारों ने टीका-टिप्पणी की थी और भारत व पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सुधारने पर इसका भी दुष्प्रभाव पड़ा था। पाकिस्तान को बार-बार जोर देते हुए यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रोपेगैंडा के तरीके विशुद्ध द्विपक्षीय, विवादास्पद और भावात्मक प्रश्नों को उठाने से ऐसे वातावरण के सृजन की दिशा में भारत के प्रयत्नों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि जिससे यह मामले सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाए जा सकते हैं।

भारत को पाकिस्तानी अखबारों की गैर-जिम्मेदाराना अटकलबाजियों को देखकर भी अफसोस हुआ जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच आतंजन संपर्क की बात कही गई है। ऐसी खबरों का कोई ठोस आधार नहीं है और राष्ट्रपति जिया के नाम एक पत्र में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने यह कहा कि “हमेशा की तरह आज भी भारत के लोग और भारत सरकार तथा मैं स्वयं दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता, सद्भाव और सहयोग संबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता, प्रादेशिक मूल्यव्यवस्था, राजनीतिक स्वतन्त्रता और प्रमुखात्मक समानता का सम्मान करने के लिए उतने ही प्रतिबद्ध हैं।”

भारत-पाक सम्बन्धों को पहुँचने वाले इन छोटे-मोटे घटकों से अविचलित रहते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ सहयोग के कई ठोस क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयत्न किए। इनमें तीर्थ-यात्रियों, व्यापारियों, पर्यटकों, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्रों के आदान-प्रदान तथा दोनों देशों के समान हित के मामलों में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। इस नीति का अनुसरण करने में भारत को अपने इस विश्वास से प्रेरणा मिली कि राजनीतिक मुलह सफाई से, अधिक सहयोग और बृहत्तर सांस्कृतिक सहयोग से और लोगों के मेल-मिलाप से भारत और पाकिस्तान दोनों की जनता को भारी लाभ होगा और इससे इस उप-महाद्वीप की शान्ति और स्थायित्व में योगदान मिलेगा।

भारत और श्रीलंका

भारत और श्रीलंका के सम्बन्ध हार्दिक और सौहार्द्रपूर्ण बने रहे। सितम्बर, 1980 में राष्ट्रपति जयवर्धन ने अपने विदेशमन्त्री के साथ भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जयवर्धन ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ

विचार-विमर्श किया जिससे दोनों देशों के बीच निकट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता मिली।

श्रीलंका में भारतीय मूल के राज्यविहीन व्यक्तियों के कारण उत्पन्न वाली समस्याओं के समाधान के लिए भारत और श्रीलंका निरन्तर कोशिश करते रहे। तरह-तरह के अनेक जटिल कारणों से इस सिलसिले में प्रगति उतनी नहीं हो सकी जितनी उम्मीद की जाती थी। दोनों सरकारें एक-दूसरे के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि इस समस्या का शीघ्रता के साथ समाधान खोजा जा सके।

इस बात के बहुत अच्छे आसार नजर आते हैं कि आगामी वर्षों में श्रीलंका के साथ हमारा आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। जनवरी, 1981 में एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिसके अन्तर्गत श्रीलंका के उद्यमकर्त्ता औद्योगिक क्षेत्र में भारत की क्षमताओं से अधिकाधिक अवगत होते जा रहे हैं। भारत की वित्तीय सहायता से दोनों देशों के बीच जो सूक्ष्म तरंग सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है वह आशा है कि आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा। भारत ने श्रीलंका को 10 करोड़ रुपये का एक और ऋण दिया है। श्रीलंका इस ऋण का उपयोग भारत से मोटर गाड़ियों के फालतू पुर्जों, परिवहन उपस्कर, रेल उपस्कर और फालतू-पुर्जों तथा ऐसी ही दूसरी चीजें खरीदने पर करेगा। सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रीडा और मचीय कलाओं के क्षेत्र में आदान-प्रदान पहले की तरह चलता रहा।

भारत और चीन

भारत-चीन सम्बन्धों को सामान्य बनाने की वर्तमान प्रक्रिया के सन्दर्भ में पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर व्यापक क्षेत्रों में पारस्परिक आदान-प्रदान को बड़ावा दिया गया। दोनों देशों में एक-दूसरे के रिहामशी संवाददाताओं (पीकिंग में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया का संवाददाता और भारत में जिन्हूग्रा का संवाददाता) को भेजने के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच सहमति के बाद पी टी आई के एक संवाददाता ने नवम्बर, 1980 में अपना कार्यभार सम्भाल लिया। इस वर्ष के दौरान कई भारतीय पत्रकारों ने चीन की यात्रा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर एम. जी. के मेनन ने 'इस्केप' द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त-सितम्बर में चीन की यात्रा की। उन्होंने चीन के अपने समकक्ष पदाधिकारियों से सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया।

अगस्त के प्रारम्भ में भारतीय सेना की एक ठुकड़ी सामान्य गश्त के दौरान भटक कर चीन के सीमा क्षेत्र में चली गई। सीमा पर शान्ति बरखाने और आपसी सम्बन्धों के सुधार की दिशा में काम करने के सम्बन्ध में दोनों सरकारों की गमक-बूझ को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने संयम से काम लिया और मोहार्द्र पूर्ण ढंग से इन सैनिकों की वापसी की व्यवस्था की गई।

4 नवम्बर को कृषिमन्त्री श्री राव धीरेन्द्र मिह कुद्ध समय के लिए पीकिंग

में रहे और उप प्रधानमंत्री बानर्जी से मित्रता और सौहार्दपूर्ण बातें की। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन भारत के साथ अपने सम्बन्धों को विकसित करने के लिए तैयार है और उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच कृषि प्रौद्योगिकी में सहयोग की व्यापक सम्भावनाएँ हैं।

चीन के पाँच सदस्यीय दल ने 24 अक्टूबर से 12 नवम्बर, 1980 तक नवेली खुली कोयला खान का दौरा किया। चीन के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल को 3 से 7 जनवरी, 1981 तक वाराणसी में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित किया गया।

दो चीनी नर्तको को भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए छात्रवृत्तिगर्ी दी गई। चीन के एक व्यापारिक दल ने जनवरी, 1981 में भारत का दौरा किया और चीन के कलावाजों की एक मण्डली फरवरी, 1981 के अन्त में भारत की यात्रा पर आई। एयर इण्डिया के एक प्रतिनिधि मण्डल ने चीनी विमान सेवा के निमन्त्रण पर 11-14 अक्तूबर, 1981 तक पोकिंग की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों विमान सेवाओं के बीच अन्तर्मार्गीय विमान करार सम्पन्न हुआ।



महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश-नीति

(Rise of Soviet Union as Super Power
and Its Foreign Policy)

“रूस की नीति अपरिवर्तनीय है.....उसके साधनों, उसकी चाहों तथा कूटनीति में परिवर्तन हो सकता है; परन्तु उसकी नीति का मार्ग-दर्शक गृह-विषय-प्रभुता एक अविचल और ध्रुव ग्रह है।” —कार्ल मार्क्स

1917 की क्रान्ति के फलस्वरूप जो सोवियत-व्यवस्था स्थापित हुई उसके कुछ ही महीनों बाद संसार के पूँजीवादी राज्यों ने मिलकर रूस के नवीन शासन का गला घोटने और उसका नामोनिशान मिटाने के विपुल प्रयास किए। यदि पूँजीवादी राज्यों की ओर से ऐसा न हुआ होता तो सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ की नीति आज कुछ दूसरी ही होती।

चारों तरफ से आन्तरिक और बाह्य खतरों को देखकर साम्यवादी शासकों ने एक ऐसा मार्ग ग्रहण किया जिससे रूसी सकटापन्न विकास के पुराने सिद्धान्तों अर्थात् आत्मरक्षा और सुरक्षा की नीति की ओर वापस लौटा जा सके और पश्चिमी प्रभाव से मुक्त देशों के साथ सन्धियाँ की जा सकें।

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक सोवियत संघ के उदय की अवस्थाएँ

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोवियत-शासन के साम्यवादी क्रान्ति से द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सोवियत कूटनीति ने अनेक रूप ग्रहण किए।

सोवियत कूटनीति विभिन्न अवस्थाओं में से होकर गुजरी—

(i) प्रथम अवस्था (1917-1921) पश्चिमी राष्ट्रों के साथ उग्र विरोध और समस्त विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार करने की थी। सोवियत-शासन के प्रारम्भिक 4 वर्ष केवल अपने अस्तित्व को बचाने के उस संघर्ष में व्यतीत हुए,

अन्ततः ट्रॉट्स्की द्वारा संगठित लाल सेना साम्यवादी शासन को स्थायित्व प्रदान करने में सफल हुई।

(ii) द्वितीय अवस्था (1921-1934) रक्षात्मक पार्यव्य (Defense Isolation) की थी। इस काल में रूस ने आत्मरक्षा की दृष्टि से विभिन्न शक्तियों के साथ सन्धियाँ सम्पन्न कीं, उनसे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाए और दूसरे देशों में साम्यवादी प्रचार करना कम कर दिया। इस अवस्था में वह सामान्यतया पश्चिमी देशों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहा और उसने राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी ग्रहण नहीं की। इस अवधि में यद्यपि रूस ने पूँजीवादी राज्यों से समझौता करने की नीति का अनुसरण किया, परन्तु कोमिन्तर्न द्वारा अन्य देशों में साम्यवादी क्रान्ति फैलाने के प्रयत्नों के कारण पश्चिमी राज्य रूस की अविश्वास व सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। इसलिए संयुक्तराज्य अमेरिका सन् 1933 से पूर्व रूस को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए उद्यत नहीं हुआ। किन्तु रूस की अधिक समय तक उपेक्षा करना सम्भव न था। रूस अब कोई सामान्य शक्ति नहीं रह गया था। वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक महान् शक्ति के रूप में उदित हो चुका था। अतः जब वुड्रोविल्ड अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो उसने सोवियत संघ को मान्यता प्रदान करने की दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिए। लन्दन में विश्व-अर्थ सम्मेलन (1933) के अवसर पर सर्वप्रथम अमेरिकी प्रतिनिधि विलियम बुलिट और रूसी प्रतिनिधि लिटविनोव की भेंट हुई। इसके बाद दोनों में एक सन्धि सम्पन्न हुई जिसके द्वारा दोनों सरकारों ने एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा और विरोध प्रचार करने वाले दलों के दमन का वचन दिया। रूस ने अमेरिका की यह बात मान ली कि वह अपने देश में आने वाले अमेरिकी यात्रियों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करेगा। इस सन्धि का यह प्रतिवार्य परिणाम हुआ कि रूस की साम्यवादी सरकार को संसार की महान् शक्तियों ने स्वीकार कर लिया।

(iii) तीसरी अवस्था (1934-1938) के काल में रूस राष्ट्रसंघ का सदस्य बना और साथ ही उसने पश्चिम के साथ सहयोग करने की नीति अपनाई। राष्ट्रसंघ में प्रवेश के बाद मई, 1935 में रूस ने अपने पिछले सभी मतभेदों एवं झगड़ों को मुलाते हुए फ्रांस के साथ पारस्परिक सहायता का 1894 जैसा सैनिक समझौता किया। इसके बाद पोलैण्ड तथा बाल्टिक राज्यों के साथ भी भास्को ने अनाक्रमण समझौते किए और टर्की तथा ग्रेट-ब्रिटेन से घनिष्ठता बढ़ाई। 16 मई, 1935 को चेकोस्लोवाकिया के साथ भी उसकी सन्धि हुई। इस तरह रूस ने फ्रांस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से नाजी आक्रमण के विरुद्ध सगठन जुड़ किया। मार्च, 1936 में बाह्य मंगोलिया के साथ एक पारस्परिक सहायता-सन्धि की गई जिसका उद्देश्य आन्तरिक मंगोलिया में जापान के प्रवेश को रोकना था। इस समय तक रूस वस्तुतः एक विशाल शक्ति-सम्पन्न देश बन चुका था।

इस सभी समझौतों और सन्धियों से रूस की स्थिति पक्का सुदृढ़ हो गई। इस समय तक साम्यवादी कूटनीति ने एक और भी नया आन्तिमारी मोड़ लिया।

देश तथा विदेश दोनों में 1934-35 में 'कॉमिन्टर्न' (Comintern) में यथावक एक सवाल उठा। विश्व-शान्ति नीति के प्रतिकूल रूस ने पाश्चात्य लोकतन्त्रीय राष्ट्रों में साम्यवादियों को फासिस्ट शासन का विरोध करने वाले बुर्जुआ दलों—उदारवादी, समाजवादी आदि के साथ मिलकर समुक्त मोर्चा (United Front) बनाने का आह्वान किया। फलस्वरूप अब प्रत्येक देश के साम्यवादी दलों ने अन्य प्रगतिशील तत्वों के साथ फासिस्टवाद के विरुद्ध समुक्त मोर्चा स्थापित किया। वास्तव में रूसी विदेश-नीति में यह बिल्कुल नया परिवर्तन था क्योंकि जो समाजवादी उदारवादी आदि उपर्युक्त सभी दल 'पूँजीवाद के पिटू' बहे जाते थे, वे 1934 के बाद अब 'साम्राज्यवाद के विरुद्ध किए जाने वाले अभियान में बहुमूल्य सहयोगी' समझे जाने लगे।

1934 से 1938 तक सोवियत रूस ने पाश्चात्य देशों के साथ सहयोग और मैत्री की नीति तो अपनाई, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से रूस और पश्चिम के मध्य कोई वास्तविक मित्रता स्थापित न हो सकी। फासिज्म को साम्यवाद के विरुद्ध तथा साम्यवाद को फासिज्म के विरुद्ध करने की अपनी युक्तियों में वह सफल हुआ और फासिज्म का हर स्थान पर विरोध करना रूसी नीति का एक मुख्य तत्त्व बन गया। हम एवं पश्चिमी देशों के मैत्री सम्बन्धों पर टिप्पणी करते हुए शुमैन (Schuman) ने ठीक ही लिखा है—'इस उद्देश-पूर्ण मैत्री भाव में पारस्परिक विश्वास का अभाव था।' वास्तव में पश्चिमी राष्ट्रों का विश्वास था कि रूस का उद्देश्य अन्तिम रूप से पूँजीवाद का विनाश करना है, इसलिए उनकी मित्रता केवल एक दिखावा मात्र है। परिणामतः वे फासिस्ट शक्तियों को साम्यवाद विरोधी तत्त्व समझकर बढ़ावा देने की नीति पर चलते रहे। ऐसे तीन प्रमुख अवसर आए जब पश्चिमी राष्ट्रों की नीति से स्पष्ट हो गया कि वे आड़े दस्त में रूस का साथ देने को तैयार नहीं हैं, उन्हें रूस पर विश्वास नहीं है और फासिस्ट आक्रमणों को रोकने की अपेक्षा उन्हें रूसी साम्यवाद को रोकने में अधिक दिलचस्पी है। पहला अवसर इटली एबीसीनिया युद्ध का था। इनमें रूस ने राष्ट्रसंघ के माध्यम से मुसोलिनी के बर्बर आक्रमण में अद्विज-अवस्था की रक्षा का भरसक प्रयास किया, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने एबीसीनिया तथा राष्ट्रसंघ की बलि देकर भी मुसोलिनी की रक्षा की। दूसरा अवसर स्पेनिश महायुद्ध का था। इस अवसर पर हमने स्पेन की जनतन्त्रीय सरकार को सहायता भेजी और एंजो-फ्रैंको सरकारों में भी फासिस्टवादी फ्रोंटों ने सहायता ली। स्टॉलिन ने अपने वक्तव्य से इस बात का स्पष्ट आभास दे दिया कि हम को पश्चिमी शक्तियों से सहयोग की आशा करना पूरी मूर्ख-भरी चिन्ता थी।

(iv) चौथी अवस्था (1938-39) में रूस ने पश्चिमी राष्ट्रों से पृथक् रहने एवं संकटपूर्ण पर्यावरण (Dangerous Isolation) की नीति अपनाई। यह स्वाभाविक था, क्योंकि पश्चिमी शक्तियों के राजनीतिज्ञों ने इस समय तक रूस को न केवल अपने वक्त्र में निकाल बाहर किया था, बल्कि पश्चिम की ओर की सोवियत रूढ़नीतिचर मुरझा-व्यवस्थाओं को बाह्य से उड़ा दिया था। सितम्बर, 1938 के

म्यूनख-ममभौते के बाद से ही रूस ने वस्तुतः अपने आपको सतटपन्न स्थिति में पाया। रूस का कोई विश्वासपात्र मित्र नहीं था। फ्रांस पर अब कोई विश्वास नहीं किया जा सकता था और ब्रिटेन का मामलों की अपेक्षा बलिन की ओर अधिक भुकाव था। रूस इस बात का भली-भाँति अनुमान लगा चुका था कि पश्चिमी शक्तियाँ जर्मनी को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जब रूस पश्चिम की तरफ से निराश हो गया तो उसने अपनी आत्म-रक्षा के, धुरी-राष्ट्रों से मैत्री के प्रयास तेज कर दिए और अगस्त, 1939 में जर्मन-सोवियत-मनाक्रमण समझौता सम्पन्न हो गया। पश्चिमी राष्ट्रों के लिए सोवियत जर्मन समझौता एक वज्रपात के समान था। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह समझौता पाश्चात्य लोकतन्त्रों के साथ उनकी मैत्री का विश्वासघात, शांति के मोर्चे का विघटक और सोवियत कूटनीति के दुरूपेण का परिचायक है। उसने यह समझौता इसलिए किया है कि इसके परिणामस्वरूप पश्चिम और पूर्व जर्मनी प्राणान्तरक सघर्ष से जुझकर शीघ्र हो जाएँ, संसार में साम्यवाद का प्रभुत्व स्थापित हो सके और रूस को पोलैण्ड तथा बाल्टिक राज्यों के प्रदेश प्राप्त हो सकें, परन्तु इस प्रकार के आरोप लगाते समय पश्चिमी राष्ट्र यह भूल गए थे कि वास्तव में किसी भी समझौते के लिए वे स्वयं उत्तरदायी थे। बार-बार जर्मनी को एक साम्यवाद-विरोधी शक्ति मानकर प्रोत्साहित कर उसे सोवियत रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। विश्वासघात का आरम्भ उन्हीं के द्वारा हुआ था।

यद्यपि रूस ने जर्मनी के साथ मनाक्रमण-समझौता कर लिया, तथापि वह जर्मनी के दुरादों को भाँपकर स्वयं को उसके विरुद्ध शक्तिशाली बनाने के लिए निरन्तर तैयारी करता रहा। सितम्बर, 1939 में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया। रूस महायुद्ध के आरम्भ में तटस्थ रहा, किन्तु अपनी सम्पूर्ण कूटनीतिक सावधानियों के बाद भी वह जून, 1941 में अपने ऊपर जर्मनी के आक्रमण को नहीं रोक सका। इस आक्रमण में समस्त धुरी-राष्ट्रों की मानव शक्ति और स्रोत कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय रण-मंच के अभिनेताओं के रूप में सोवियत नेताओं ने अपना पेंतरा बदला और अब वे नाजी जर्मनी के सहायक न होकर राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ बन गए तथा प्रजातन्त्रात्मक ब्रिटेन का समर्थन करने लगे। 13 जुलाई 1941 को सोवियत रूस और ब्रिटेन ने एक पारस्परिक सहायता-समझौता किया जो मई, 1942 में औपचारिक अंग्ल-सोवियत सन्धि के रूप में परिणत हो गया। 24 सितम्बर, 1941 को सोवियत संघ ने अटलाण्टिक चार्टर को स्वीकार करते हुए यह घोषणा की कि सोवियत संघ अपनी विदेश-नीति को राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित करता था और करता है। वह प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता व प्रादेशिक अखण्डता के अधिकार की रक्षा करता है तथा उनके इस अधिकार को स्वीकार करता है कि वह अपने उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था एवं सरकार का रूप निश्चित कर लें। 1 जनवरी, 1942 को सोवियत रूस ने संयुक्तराष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर धुरी राष्ट्र-विरोधी संघ में औपचारिक रूप से सम्मिलित हो गया।

जर्मन प्रकार ने अपने सभी भावमूल को सोवियेटिज्म के विरुद्ध समस्त यूरोप का संघर्ष बताया। अधिकृत रूप से यूरोप में जर्मनी की नीति केवल साम्यवाद विरोधी ही नहीं थी बल्कि रूस-विरोधी भी थी। इसके कारण सोवियत नेताओं को साम्यवाद एवं रूसी राष्ट्रवाद में एकरा स्थापित करनी पड़ी। रूस ने मार्क्सवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रचार को कम कर रूसी तथा राष्ट्रवादी प्रचार की मात्रा को बढ़ा दिया। इस प्रकार सोवियत रूस ने द्वितीय साम्राज्यवादी युद्ध को प्रचार द्वारा महान् देशभक्तिपूर्ण युद्ध के रूप में परिणत कर दिया। युद्ध की देशभक्तिपूर्ण प्रकृति को सिद्ध करने के लिए औपचारिक रूप से कोमिन्टर्न को मई, 1943 में समाप्त कर दिया गया और इसके कार्य सोवियत साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के विदेश विभाग को सौंप दिए गए। युद्ध के समय चर्च ने भी साम्यवादी सरकार को राष्ट्रवाद के नाम पर समर्थन प्रदान किया। इन सब घटनाओं ने सोवियत सरकार की नीति और तकनीकी ज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए और यह गमभाज जाने लगा कि अब यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय मान्दोलन की अपेक्षा राष्ट्रवादी मान्दोलन को और अनुकूल है।

युद्ध के सोवियत लक्ष्य (The Soviet War Aims)

सोवियत संघ द्वितीय विश्वयुद्ध द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता था और उसे क्या मिला, इन दोनों के बीच सम्बन्ध देखना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि सोवियत राजनीति में उसके उद्देश्यों का पता लगाना असम्भव-सा है। युद्ध काल में सोवियत सरकार द्वारा प्रसार के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम अपनाया गया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। सोवियत संघ के युद्ध के लक्ष्यों को इसके मैनिक और वृत्तीय कार्यो द्वारा ही जाना जा सकता है। कई एक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सोवियत नेता जारशाही साम्राज्यवादी लक्ष्यों से प्रेरित थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उनके पद-विह्वो पर ही चल रहे थे तथापि जारशाही द्वारा सोवियत रूसी हितों का और जनता की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता था, इसलिए उसे अपनाया जाना उपयोगी था, युद्ध द्वारा रूस ने पहले तो उन प्रदेशों को प्राप्त करने का प्रयास किया जो जारशाही के समय दूसरे देशों द्वारा ले लिए गए थे। मुद्गर पूर्व में रूसी-जापानी युद्ध में हार के कारण जारशाही ने घनेक प्रदेशों पर से अधिकार छोड़ दिया था। इस प्रसारवादी उद्देश्यों के साथ-साथ सोवियत सरकार ने युद्ध में कुछ-एक ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने की भी चेष्टा की जो जारशाही सरकार द्वारा रूसी साम्राज्य के हित में नियोजित किए गए थे, किन्तु प्राप्त नहीं किए जा सके। इन उद्देश्यों में पहला यह था कि यूरोप में प्रभाव का क्षेत्र इतना अधिक बढ़ाया जाए कि वहाँ सोवियत मैनिक और वृत्तीय मुरक्षित रह सकें। दूसरे, बाले मागर के दर पर नियन्त्रण किया जाए और मोगरे, जब कभी भी आवश्यक प्राप्त हो निवृत्त मध्य एवं मुद्गर पूर्व में तथा विश्व में हर जगह सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ाया जाए।

प्रत्येक विदेशी साम्यवादी का यह कर्तव्य माना गया कि वह अपने पूरे प्रभाव से प्रत्येक सोवियत सैनिक एवं कूटनीति का समर्थन करे। ऐसा करते समय यदि उसे अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्रवहेलना भी करनी पड़े तो वह पीछे न हटे, क्योंकि सोवियत सरकार के लक्ष्य एवं उद्देश्य सर्वोच्च हैं और वह विश्व-साम्यवादी आन्दोलन की आत्मा है। वैसे सोवियत नेताओं की विदेशी साम्यवादियों के प्रयासों पर अधिक भरोसा एवं विश्वास नहीं था, किन्तु फिर भी वे प्रसारवादी कूटनीति को चालू रखना चाहते थे। उनके लिए द्वितीय विश्वयुद्ध सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध नहीं था बल्कि यह एक ऐतिहासिक सोपान था जिससे विश्व साम्यवाद की ओर मुड़ सके। स्टालिन ने युद्ध की प्रकृति पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि यह युद्ध अतीतकालीन युद्धों की भाँति नहीं है। इसमें जो कोई भी जिस प्रदेश पर अधिकार कर लेगा उस पर अपने स्वयं की सामाजिक व्यवस्था लाद देगा। जहाँ तक उसकी सेनाएँ पहुँच सकती हैं, वहाँ तक वह अपनी सामाजिक व्यवस्था लागू कर सकता है। स्टालिन का कहना था कि “यह युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और हम पन्द्रह-बीस वर्षों में क्षतिपूर्ति कर पाएँगे। इसके बाद पुनः नया युद्ध छिड़ेगा।” इस प्रकार सोवियत नेताओं ने द्वितीय विश्वयुद्ध में यद्यपि विश्व-साम्यवाद का प्रचार किया, किन्तु उनका मुख्य ध्यान सोवियत रूस की राजनीतिक शक्ति पर था। उन्होंने सज्जता के साथ अपने सैनिक एवं कूटनीतिक कार्यों को समन्वित किया।

युद्धकालीन सोवियत कूटनीति (Soviet War-time Diplomacy)

दिसम्बर, 1941 में ग्रेट-ब्रिटेन के विदेश सचिव एग्नेसी ईडन मास्को गए और इस प्रकार सोवियत नेताओं को पश्चिमी मित्रों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ। इस समय लाल सेना ने जर्मनी के सैनिकों को मास्को के दरवाजों पर रोक दिया था। सम्मेलन के दौरान स्टालिन अपनी अन्तिम विजय के प्रति आश्वासन था। स्टालिन ने इस सम्मेलन में युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करने पर जोर दिया, किन्तु ईडन ने कहा कि ग्रेट-ब्रिटेन सीमा-सम्बन्धी प्रश्नों पर युद्ध के बाद ही विचार करने के अमेरिकी विचार से सहमत है। मई, 1942 में जब मोलोटोव आंग्ल-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए लंदन गए तो उन्होंने पुनः सोवियत माँग को दोहराया किन्तु ग्रेट-ब्रिटेन ने पुनः इसे मानने से मना कर दिया।

सोवियत संघ की यूरोप में बड़ी महत्वाकांक्षाएँ थी और ग्रेट-ब्रिटेन इनसे परिचित था। स्टालिनग्राड के युद्ध के बाद सोवियत सेना पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय बन गई और अब सोवियत सरकार को सफलता का महान् आश्वासन मिला। चाहे पश्चिमी शक्तियों की परवाह किए बिना ही पूर्वी केन्द्रीय यूरोप में उसने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। सोवियत महत्वाकांक्षाओं से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाला देश पोलैण्ड था। पोलैण्ड की निष्कासित सरकार ग्रेट-ब्रिटेन में स्थित

थी। उसका सोवियत संघ के प्रति पर्याप्त कटु अनुभव था क्योंकि इसने सन् 1939 में पोलैण्ड को नष्ट करने में भाग लिया था। सोवियत संघ ने यह प्रदर्शित किया कि युद्ध के बाद पोलैण्ड के सगठन में उनका हाथ है और इसके बाद उसने सोवियत सेना के अधीन पोलिश संघ के देशभक्तों को मास्को में जमा किया जो साम्यवादी पोलिश सरकार की नाभि का काम कर सकें। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ ने चेकोस्लाव, यूगोस्लाव और रूमानिया की ब्रिगेड भी गठित की जिसमें अधिकृत सिपाहियों को भर्ती किया गया। मास्को ने लंदन में किंग पीटर II के अधीन यूगोस्लाव सरकार से वार्ता जारी रखी और कैरो में जार्ज द्वितीय के अधीन यूनानी सरकार से भी सम्पर्क बनाए रखा। सोवियत संघ ने लंदन स्थित राष्ट्रपति एडवर्ड वीनस (Edward Venus) के अधीन यूगोस्लाव सरकार से भी मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम रखे। जुलाई और सितम्बर, 1943 में स्वतन्त्र जर्मनी के लिए राष्ट्रीय समिति और जर्मन अधिकारियों का संघ मास्को में गठित किया गया। इनका निर्देशन निष्कासित जर्मनों द्वारा किया जाता था, किन्तु इनमें जर्मन अधिकारी भी शामिल थे। उस समय सम्पूर्ण जर्मनी या उसके किसी भाग पर सोवियत संघ के अधिकार के आसार दूर दिखाई दे रहे थे। उस समय मास्को में स्थित जर्मन समूहों का तत्कालीन कार्य यह था कि जर्मन सिपाहियों को आत्म-समर्पण के लिए समझा कर उनकी युद्ध-क्षमता एवं प्रयासों को कम किया जाए। अक्सर आने पर इनका उपयोग जर्मनी पर सोवियत प्रभाव बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था।

पश्चिमी मित्र एवं सोवियत नीति

सोवियत नीति के असन्तुलन ने पश्चिमी शक्तियों को भ्रम में डाल दिया तथा उनको सोवियत लक्ष्यों के वास्तविक रूप का अनुमान नहीं हो सका। सोवियत संघ द्वारा जो भी आश्वासन दिए जाते थे उनको प्रारम्भ में अमेरिका द्वारा ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता था, किन्तु ग्रेट-ब्रिटेन के लोगो को उनके बारे में विश्वास कम था। सोवियत संघ का प्रसार यूरोप में होता जा रहा था, किन्तु उच्च स्तर के अमेरिकी कूटनीतिज्ञों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अमेरिकी सरकार एवं जनता यह मान कर चल रही थी कि युद्ध के बाद पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव होना ही चाहिए। उन्होंने सोवियत प्रभाव को इन क्षेत्रों में प्रजातन्त्र की स्थापना के विपरीत नहीं माना। उनका तर्क था कि यदि ऐसा कुछ होता तो सोवियत संघ द्वारा अष्टाष्टाष्ट चार्टर एवं संयुक्तराष्ट्रों की घोषणा में विश्वास ही क्यों किया जाता। उस समय संयुक्तराज्य अमेरिका में साम्यवाद एवं सोवियत मामलों के कुछ ही ऐसे जानकार थे जो सोवियत संघ के इरादों की सन्देह की नजर से देखते थे। उनका विचार था कि सोवियत संघ द्वारा पड़ोसियों को मित्र बनाने पर जोर दिए जाने के पीछे कुछ रहस्य है और वह सम्भवतः यह है कि उनके पड़ोसी भी साम्यवादी देश बन जाएँ; क्योंकि लेनिन की दो गुट की विचारधारा के अनुसार पूँजीवादी एवं समाजवादी गुट भी कभी मित्र हो ही नहीं सकते और इसलिए एक राष्ट्र सोवियत

संघ का दोस्त तभी बन सकता है जबकि वह चाल शण्डा के नीचे आ जाए। सामान्यतः अमेरिकी सरकार एवं जनता को सोवियत मंत्री में कोई शक नहीं था और सामान्य पश्चिमी हित के विषय उन्होंने ग्रेट-ब्रिटेन को सौंप दिए।

मित्र राष्ट्रों के विदेश-मन्त्रियों का प्रथम सम्मेलन मास्को में अक्टूबर, 1943 में हुआ। इस समय अमेरिकी राज्य सचिव कार्डेल हल (Cordell Hull) एवं ब्रिटिश विदेश मन्त्री ईडन (Eden) ने सोवियत एवं पोलिश सरकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, किन्तु कोई सफलता न मिली। अमेरिकी दृष्टिकोण पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त स्टालिन ने कार्डेल हल को यह कहा कि जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सोवियत संघ जापान के विरुद्ध युद्ध में हस्तक्षेप करेगा। सोवियत संघ ने अप्रैल, 1941 में जापान के साथ अनाक्रमण सन्धि की थी और इस प्रकार वा कोई इरादा इस सन्धि का स्पष्ट उल्लंघन था। अनैतिक होते हुए भी यह आश्वासन उन अमेरिकी सैनिक नेताओं को पसन्द आया जो जापान के विरुद्ध युद्ध में सलग्न थे, किन्तु युद्ध के अन्तिम क्षणों तक भी जनरल मार्शल प्रशान्त युद्ध में सोवियत सहायता के वायदे को भुलाना रहा; साथ ही यूरोप में सोवियत प्रसारवादी नीतियों से भी वह निश्चिन्त रहा।

तेहरान सम्मेलन (The Teheran Conference)

तेहरान में 28 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1943 तक तीन बड़े राष्ट्राध्यक्षों का प्रथम सम्मेलन हुआ। चर्चिल, रुजवेल्ट एवं स्टालिन ने ईरान की राजधानी में पारस्परिक हित के विषयों पर विचार-विमर्श किया। यह तय किया गया कि ब्रिटेन, अमेरिका मिलकर 1944 में फ्राँस पर आक्रमण करेंगे और सोवियत संघ जर्मनी के साथ अपना युद्ध समाप्त कर प्रशान्त महासागर के युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस विचार-विमर्श में पोलैण्ड का प्रश्न मुख्य बना रहा। चर्चिल ने यह सोचा कि शायद सोवियत संघ और पोलैण्ड की सरकारों के बीच समझौता होने में कुछ बाधा सोवियत-पोलिश सीमा का प्रश्न है, अतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि 1941 की सीमा को स्वीकार कर लिया जाए और पोलैण्ड को पूर्व में जो क्षति होगी उसे पश्चिम में जर्मनी के भागों से पूरा कर दिया जाए। पक्षि यह प्रस्ताव अटलाण्टिक चार्टर का उल्लंघन था, तथापि व्यावहारिक सुविधा के लिए इसे अपनाया गया। स्टालिन ने अग्रिम ही इस विचार को अपना लिया, किन्तु पोलिश सरकार से मनमुटाव कायम रहा। रुजवेल्ट इस सम्बन्ध में चुप ही रहे। चर्चिल ने एक अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार जर्मन निवासियों को एजियन द्वीपों (Aegean Islands) से निकाल कर युद्ध का विस्तार भूमध्यसागर में कर दिया जाए; किन्तु यह कार्यक्रम रुजवेल्ट तथा स्टालिन दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया। यह कार्यक्रम असफल रहा क्योंकि यह टर्की के सहयोग पर निर्भर करता था। जब पश्चिमी नेता कैरो में राष्ट्रपति इस्मैत इनोनू (Ismet Inonu) से मिले तो उसने टर्की को सब तक समझाने से मना कर दिया जब तक कि युद्ध का फंसला न हो जाए।

राष्ट्रपति बेनेस (Benes) तेहरान होते हुए मास्को गए और ब्रिटिश परामर्श

के विरुद्ध 13 अक्टूबर, 1943 को सोवियत-चैकोस्लोवाक सन्धि समझौता कर लिया। वेनस मूल रूप से प्रजातन्त्र का समर्थक एवं पश्चिमी राजनीति की ओर झुका हुआ था, किन्तु म्यूनिख समझौते में ब्रिटेन व फ्रांस के योगदान से वह नाराज था। इसके अनिरीक्त उसे यह विश्वास हो गया था कि पश्चिमी शक्तियों ने पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप से अपना हाथ खींच लिया है, अतः उसने सोवियत संघ के साथ सन्धि करना उपयुक्त समझा। चैकोस्लोवाकिया के विदेश-मन्त्री जॉन मेसेरिक (Jan Masaryk) ने सन्दन में अपने साथियों के सम्मुख इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा था कि 'हम आइजनहॉवर के नक्शे में नहीं हैं।'

जब नॉर्वे ने सन्दन लौटने पर पोलिश सरकार की 1941 की सीमा का बलिदान कर सोवियत रूस से समझौता करने की बात कही तो पोलिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर पश्चिमी शक्तियों को यह विश्वास हो गया कि पोलिश सरकार की अबुद्धिमत्ता के कारण ही सोवियत रूस से उसका समझौता नहीं हो पा रहा किन्तु 1947 में घटने वाली घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वेनस की बुद्धिमत्ता भी उसकी सरकार को बचाने में सफल नहीं हो सकी।

पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप पर सोवियत विजय

(The Soviet Conquest of East-Central Europe)

जून, 1944 में मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस पर आक्रमण किया। इस अवसर पर सोवियत सेना 1941 की सीमा पर पहुँच गई तथा वहाँ से उसने पोलैण्ड, रूमानिया तथा बाल्टिक राज्यों पर आक्रमण करने का कार्यक्रम बनाया। 22 जून, 1944 को इसने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप जुलाई के अन्त तक वह विस्तुला (Vistula) तक पहुँच गया। 1 अगस्त, 1944 को सोवियत सेना वार्सा (Warsaw) पहुँच गई तथा वहाँ सोवियत संघ के रेडियो प्रसारण द्वारा उबसाने पर पोलिश भूमिगत सेना जर्मनों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। फिर भी विद्रोहियों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया, किन्तु पोलिश तथा पश्चिमी सरकारों के प्रयास भी निरर्थक गए। ब्रिटिश तथा अमेरिकी जहाज जब आक्रान्त वार्सा को सामग्री पहुँचाने के लिए जाते थे तो उन्हें सोवियत सेना द्वारा अधिभूत भूमि पर नहीं रुकने दिया जाता था। यदि वे रुकते भी थे तो रूसी वायुयान भेदी बन्दूकों के निशाने बना दिए जाते थे।

इस व्यवहार के स्पष्टीकरण के रूप में सोवियत सरकार द्वारा यह तर्क दिया जाता था कि सोवियत हार्ड कमाण्ड में रणनीति की दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि कुछ समय तक विस्तुला से आगे न बढ़ा जाए। विचारकों का कहना है कि यह व्यवहार शुद्ध रूप से एक राजनीतिक चाल थी। वार्सा में जो नेतृत्व उभर रहा था वह साम्यवादी नहीं था और ग्रेट-ब्रिटेन स्थित पोलिश सरकार को मान्यता दे रहा था। सोवियत संघ ने मई, 1944 में मास्को में तदर्थ पोलिश सरकार की रचना कर दी थी। वह वार्सा में पूँजीवादी प्रतिपक्षियों की सहायता करने में कोई रुचि नहीं लेती थी। दो माह की अमानवीय लड़ाई के बाद 2 अक्टूबर, 1944 को जर्मनों द्वारा उपश्रियों को दबा दिया गया।

जब सोवियत सेना पोलैण्ड के विरुद्ध खड़ी थी तो उसने बाल्टिक एव बल्कान की ओर भी अपनी टुकड़ियाँ भेजना प्रारम्भ किया। जर्मनी के पूर्वी प्रदेश विजयी मित्रराष्ट्रों की ओर मिलने के लिए तैयार बैठे थे। वे सम्भवतः पश्चिमी देशों के सम्मुख आत्म-समर्पण को प्राथमिकता देते, किन्तु जब सोवियत सेनाएँ उनके ऊपर हावी हो गईं तो उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। 25 अगस्त, 1944 को फिनलैण्ड ने हथियार डाल दिए और दस दिन बाद सोवियत फिनिश युद्धबन्दी समझौता क्रियान्वित हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार युद्धबन्दी समझौता मुख्य रूप से एक सैनिक परिपत्र होता है जिसका प्रर्थ यह है कि जब तक शान्तिवार्ता के बाद समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई लड़ाई नहीं होगी, किन्तु सोवियत सघ ने किसी शान्ति-सम्मेलन की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा और तुरन्त ही फिनलैण्ड तथा जर्मनी के अन्य पूर्वी उपराज्यों के साथ सम्बन्ध निश्चित करना उचित समझा।

इसी समय रूमानिया ने भी मित्रराष्ट्रों की ओर मिलने का निर्णय किया। यह कहा जाता है कि रूमानिया की सरकार ने पश्चिमी शक्तियों से गुप्त समझौता करने का प्रयास किया था, किन्तु उन्होंने इसे सोवियत रूस के ही हवाले कर दिया। रूमानिया का प्रतिनिधिमण्डल मास्को गया तथा उसने 12 सितम्बर, 1944 को युद्धबन्दी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। रूमानिया को सह-योद्धा का स्तर प्रदान कर दिया गया तथा रूमानिया की सेनाएँ मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध के अन्त तक लड़ती रहीं।

रूमानिया के झुकने के कारण सोवियत सेना दक्षिण में डेन्यूब (Danube) तथा बल्गारिया की ओर तेजी से बढ़ सकती थी तथा कार्पेथियन पर्वतमाला को पार कर पश्चिम में हंगरी की ओर बढ़ सकती थी। बल्गारिया ही एकमात्र ऐसा पश्चिमी उपराज्य था जिसने सोवियत सघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के बजाए पश्चिमी मित्रदेशों के विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा की थी। कुछ समय तक तो बल्गारिया की सरकार पश्चिमी देशों के साथ आत्मसमर्पण के लिए गुप्त-वार्ता करती रही, किन्तु बल्कान में मित्रराष्ट्रों की सेना नहीं थी, अतः वह ऐसा नहीं कर सकती थी। 5 सितम्बर, 1944 को बल्गारिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सोवियत सघ ने इस समस्या का समाधान कर दिया। सोवियत सेना ने डेन्यूब पार कर बिना किसी विरोध का सामना किए ही देश पर अधिकार कर लिया। 28 अक्तूबर, 1944 को युद्धबन्दी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बल्गारिया का प्रतिनिधिमण्डल मास्को गया। बल्गारिया को भी सह-योद्धा का स्तर प्राप्त हो गया तथा उसकी सेनाएँ मित्रराष्ट्रों के पक्ष में मिस गईं।

हंगरी इस दृष्टि से कम सौभाग्यशाली था। रूमानिया, स्लोवाकिया एव यूगोस्लाविया को रोदने के बाद सोवियत सेनाएँ हंगरी पर चढ़ आईं। एडमिरल निकोलस होर्बी के शासन में हंगरी की सरकार के अधीन पश्चिमी-मित्रों से सन्धि करना चाहती थी, किन्तु उसे भी सोवियत रूस के हवाले कर दिया गया। 15 अक्तूबर को हंगरी ने जर्मनी से अपने मंत्री सम्बन्ध समाप्त करने की घोषणा की तथा सघर्ष

थे, उन्होंने इन कार्यक्रमों को रणनीति की दृष्टि में अनुपयुक्त एवं हल्का बताया। सब यह है कि प्रथम विश्वयुद्ध के समय इस क्षेत्र में इटली की सेना को आगे बढ़ने के बजाए बुरी तरह मार खानी पड़ी थी। जब चर्चिल ने आइजनहावर के मुख्यालय में जाकर यह बात कही तथा इसके पक्ष में तर्क प्रदान किए तो इके (Ike) ने कहा, 'नहीं' वह दोपहर बाद तक 'नहीं' कहता गया और अन्त में भी उसने अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक रूप में 'नहीं' ही कहा।

चर्चिल का प्रतिशत मिद्दान्त (Churchill's Percentage Deal)

चर्चिल आगामी से ही हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मिनम्बर, 1944 में द्वितीय क्वेबेक सम्मेलन (Quebec Conference) में हज्जेल्ट के सामने भी इन बातों को रखा। इन समय राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदों में व्यस्त था। साथ ही वह नाम्यरादी खतरे की अपेक्षा माजीवाद के सम्भावित खतरे से अधिक परेशान हो रहा था, तथापि उसने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया कि चर्चिल अकेला ही स्टालिन के साथ समझौता कर ले। अक्तूबर, 1944 में चर्चिल तथा ईडन मास्को गए। यहाँ उन्होंने पुनः पोलैण्ड के प्रश्न को सुझाने की बात कही। किन्तु रूसी तानाशाह अधिक से अधिक केवल इस बात पर सहमत हुआ था कि लन्दन के पोलों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए पोलिश समिति में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। स्टालिन ने अन्य ब्रिटिश सुझावों के प्रति अधिक अकृपा रख अपनाया। इन अवसर पर चर्चिल ने स्टालिन की प्रतिशत का विचार सुझाया जिसके अनुसार बल्कन में उत्तरदायित्व का प्रतिशत के आधार पर विभाजन करना था। उदाहरण के लिए, रूमानिया पर 90 प्रतिशत सोवियत और 10 प्रतिशत पश्चिमी प्रभाव रहे; इसी तरह, बल्गारिया पर 75 प्रतिशत सोवियत और 25 प्रतिशत पश्चिमी प्रभाव; यूनान पर 90 प्रतिशत पश्चिमी और 10 प्रतिशत सोवियत प्रभाव; यूगोस्लाविया पर 40 प्रतिशत पश्चिमी और 60 प्रतिशत सोवियत प्रभाव तथा हंगरी पर 50 प्रतिशत सोवियत एवं 50 प्रतिशत पश्चिमी प्रभाव रहे। स्टालिन ने यह प्रस्ताव बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। उत्तरी एड्रियाटिक में ब्रिटेन के बने रहने की योजना को भी उसने इसी प्रकार स्वीकार कर लिया।

पर लौटने पर चर्चिल ने देखा कि उसके स्वयं के जनरल पूर्ण अमेरिकी सहायता के बिना इस कार्यवाही के रहने के लिए उत्सुक नहीं थे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यह कदम फरवरी, 1945 से पूर्व उठाना प्रभावकारी नहीं रहेगा। दिसम्बर, 1945 में उसने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इस लेन-देन का एकमात्र फायदा चर्चिल को यह हुआ कि यूनान में अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हो सका। अक्तूबर में ब्रिटेन की सैनिक टुकड़ियाँ यूनान तथा उसके आगे तक पहुँच गईं। दिसम्बर की भारी सड़ाई में यूनानी साम्यवादियों ने एथेन्स की अधिकार में कर लिया। यद्यपि राजधानी में इनकी हालत खराब कर दी गई, तथापि देहली की सड़ों में साम्यवादियों की नहीं दबाया जा सका और वहाँ यह-संघर्ष वर्षों तक चलता

रहा। सोवियत सरकार ग्रेट-ब्रिटेन के साथ समझौते के परिणामस्वरूप इतनी सीमित रही कि उसने बल्कन क्षेत्र में आगे बढ़ना रोक दिया। 11 अक्टूबर, 1944 को बेलग्रेड को अधिकार में करने के बाद सोवियत सेना उत्तर में बुडापेस्ट की ओर मुड़ गई। जर्मनी ने हंगरी की राजधानी को अपने अधिकार में करने के लिए भरसक प्रयत्न किए। हमारी ओर सोवियत सेना ने 17 जनवरी, 1945 को वार्सा पर अधिकार कर लिया। वार्सा और बुडापेस्ट पर अधिकार 12 जनवरी, 1945 के अन्तिम सोवियत आक्रमण का भाग था। सोवियत सेनाएँ बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वार्सा होती हुई पश्चिम विप्रता, प्राग, बर्लिन की ओर आगे बढ़ी।

याल्टा सम्मेलन (The Yalta Conference)

सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति पर याल्टा सम्मेलन ने एक रोक लगा दी जो 'तीन बड़ों' का द्वितीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में सामान्यतः सोवियत नेताओं ने उन विषयों की रक्षा का प्रयास किया जो सोवियत सेना प्राप्त कर सकती थी। सोवियत रूस पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप पर तो अधिकार कर ही चुका था। याल्टा में सोवियत नेताओं की समस्या यह थी कि वे दश प्रदेशों में अपने अधिकार पर पश्चिम की मान्यता प्राप्त करले। जहाँ तक अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का सवाल है वह पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप की ओर से उदासीन थे और इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत आणा-पीछा करके बात मान ली, किन्तु चर्चिल ने कई कठिनाइयाँ उपस्थित की। सबसे बड़ा प्रश्न तो पोलैण्ड की समस्या का था जिसने याल्टा में इन 'तीन बड़ों' का ध्यान केन्द्रित रखा। पोलैण्ड की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चिल तेहरान-सम्मेलन में पहले ही यह भुभाव दे चुके थे कि पोलैण्ड रूस की क्षतिग्रस्त को पूर्वी भाग में चुकाएगा और पश्चिम में जर्मनी के प्रदेश से इसकी पूर्ति कर लेगा। अब प्रश्न यह था कि क्षतिपूर्ति की मात्रा क्या हो? सोवियत नेताओं का प्रस्ताव था कि वे आडर-नैस (Oder Neisse Line) और पूर्वी प्रशा के उत्तरी भाग को अपने लिए सुरक्षित रखेंगे जिसमें कोनिसबर्ग भी सम्मिलित था। पश्चिमी नेताओं के मतानुसार कोनिसबर्ग युक्त पूर्वी प्रशा के उत्तरी भाग तक तो जान ठीक थी किन्तु इसके प्रतिरिक्त और कुछ माँगना बहुत अधिक हो जाता। इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका। ब्रिटेन ने पोलिश सरकार और सोवियत सरकार के बीच समझौते के प्रयासों को टुकरा दिया और अब वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की पोलिश समिति को मान्यता देने के लिए तैयार हो गए। यह समिति मास्को में पोलैण्ड की सरकार के रूप में मानी गई। ग्रेट-ब्रिटेन ने इस बात पर जोर दिया कि इस समिति में सन्दन में रहने वाले पोलों के कुछ प्रतिनिधि होने चाहिए। सोवियत नेताओं ने सिद्धान्त रूप से यह बात मान ली, किन्तु ब्रिटेन तथा सोवियत सच के नेता यह समझौता करने में असमर्थ रहे कि सिद्धान्त को कैसे त्रिपान्वित किया जाए। इस प्रश्न को आगे अध्ययन के लिए एक विशेष आयोग को सौंप दिया गया जिसमें सोवियत विदेश कमीसार एवं मास्को स्थित ग्रेट-ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूत थे।

पूर्वी केन्द्रीय यूरोप में ब्रिटिश-निराशा का एक अन्य कारण यह था कि वह

सन्दन-स्थित यूगोस्लाव सरकार को समर्थन दे रहा था। इस प्रश्न पर वाल्टा सम्मेलन में सोवियत नेताओं ने उसका ध्यान खींचा और ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया तथा इसके आधार पर मार्शल टीटो और लन्दन स्थित यूगोस्लाव प्रधान मन्त्री ईवान सुवासिक (Ivan Subasic) ने एक समझौता किया जिसमें नई यूगोस्लाव सरकार में विभिन्न प्रजातन्त्रात्मक दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व (Token Representation) देने की व्यवस्था की गई। यह सरकार टीटो के अधीन कार्य करेगी और वहाँ राजतन्त्र अथवा गणराज्य की स्थापना की बात जनमत के आधार पर तय की जाएगी।

सामान्य रूप से पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप में स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की गारन्टी के सम्बन्ध में अमेरिका द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि स्वतन्त्र यूरोप के सम्बन्ध में एक घोषणा जारी की जाए जिससे प्रचीन मित्रराष्ट्रों द्वारा यूरोप के स्वतन्त्र लोगों को उनकी मर्जी की प्रजातन्त्रात्मक सस्था बनाने में सहायता की जाए। यह भट्वाटिक चार्टर के अनुरूप होगा। सोवियत नेता इस प्रस्ताव से सहमत हो गए क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि यूरोप की जनता किस प्रकार की प्रजातन्त्रात्मक सस्थाएँ चाहती है। कहा जाता है कि उन्होंने स्वतन्त्र यूरोप सम्बन्धी घोषणा को उसी प्रकार बिना किसी परेशानी के स्वीकार किया जिस प्रकार बाद में बिना किसी परेशानी के उसे तोड़ दिया।

सोवियत रुचि का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जर्मनी था। सितम्बर, 1944 में लन्दन में यूरोपीय परामर्शदाता परिषद् (European Advisory Council) में जर्मनी के भावी क्षेत्रों पर सहमति हो चुकी थी। अमेरिकी सैनिक प्रतिनिधि इस परिषद् में जर्मनी के भागों को हस्तगत करने के लिए अमेरिकी सेना को उलझाने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि अमेरिका जापान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, अतः जर्मनी में उसे अधिक नहीं उलझना चाहिए। सन् 1937 के जर्मनी के क्षेत्र का 52 प्रतिशत भाग जिनमें कि 48 प्रतिशत जनता रहती थी, सोवियत क्षेत्र माना गया। वह क्षेत्र उस क्षेत्र की प्रपेक्ष अधिक था जो सोवियत सेना ने अधिकृत किया था। जर्मनी का प्रशासन मित्रराष्ट्रों द्वारा मिलकर करना था और इसके लिए बर्लिन में मित्रराष्ट्रों की नियन्त्रण-परिषद् स्थापित की गई। बर्लिन का अधिकांश भाग सोवियत क्षेत्र में आता था। इसको भी अनेक भागों में बाँटा जाना था, किन्तु प्रशासन मिलकर किया जाना था। बर्लिन तक पहुँचने के तरीके पर यूरोपीय परामर्शदाता-परिषद् में कोई विचार नहीं किया गया क्योंकि अमेरिकी सैनिक अधिकारियों के मतानुसार जर्मन-संचार-व्यवस्था के बारे में भली-भाँति जाने बिना यह सब सोचना गलत होता। वाल्टा में 'तीन बड़ों' ने यूरोपीय परामर्शदाता-परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसमें केवल यह परिवर्तन किया गया कि फ्रांस के लिए एक भाग और दिया जाए जो ब्रिटिश तथा अमेरिकी भागों में से निमित्त किया जाए।

जर्मनी के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात क्षतिपूर्ति की थी। सोवियत रुस का कहना था कि इसके बिना उसका युद्धोत्तर रचना-कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता।

याल्टा सम्मेलन में रूस ने यह प्रस्तावित किया कि जर्मनी सामान्य और सेवा के रूप में 20 मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति दे और इसमें से आधी पर सोवियत रूस का अधिकार हो। पश्चिमी देश इस बात पर सहमत थे कि जर्मनी को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, किन्तु इस क्षतिपूर्ति की मात्रा कितनी हो इसके सम्बन्ध में सहमति नहीं थी। सोवियत नेता रुजवेल्ट द्वारा सुझाए गए शर्तविहीन आत्मसमर्पण के सूत्र को मान रहे थे, किन्तु जर्मनी के भविष्य के सम्बन्ध में कोई वास्तविक समझौता न कर सके। याल्टा में 'तीन बड़ों' ने केवल इस बात पर सहमति प्रकट की कि वे जर्मनी में सैनिक शक्ति तथा शस्त्र-शक्ति को घटा सकेंगे तथा इन समस्याओं को आगे अध्ययन के लिए आयोग को सौंप सकेंगे।

उस समय जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त होने को था, इसलिए याल्टा सम्मेलन में तेहरान की अपेक्षा सुदूरपूर्व की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया गया। सोवियत नेता यह जानना चाहते थे कि जापान पर विजय के बाद उनको क्या हिस्सा दिया जाएगा, इस बात को पहले ही तय कर लिया जाए। जिस समय यूरोपीय मामलों पर सौदेबाजी हो रही थी, उस समय पश्चिमी हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व ग्रेट-ब्रिटेन पर छोड़ा गया। किन्तु जब सुदूरपूर्व के मामलों पर सौदेबाजी हुई तो यह उत्तरदायित्व सोवियत रूस पर डाला गया। सोवियत नेताओं ने अपने इस आश्वासन को दोहराया कि जर्मनी के साथ अपना युद्ध समाप्त करने के बाद दो या तीन महीने के अन्दर-अन्दर रूस जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाएगा। किन्तु इस समय उसने इसके लिए कीमत माँगी और वह यह थी कि सन् 1904 में जापान के आक्रमण द्वारा जो सोवियत अधिकार छीन लिए गए हैं वे उसको वापस मिल जाएँ। इस प्रकार साम्यवादी सोवियत सघ जारशाही साम्राज्यवाद के अवशेषों को बनाए रखने में पूरी रुचि ले रहा था।

सोवियत सघ के इन दावों ने चीन के हितों को बहुत प्रभावित किया, किन्तु चीन याल्टा सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने रूस की माँगों को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि इन पर चाँगकाई शेक की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। यह स्वीकृति प्राप्त करने का उन्हें विश्वास था। इसके बदले सोवियत नेताओं ने चीन की राष्ट्रवादी सरकार का समर्थन करने का आश्वासन दिया जिससे अमेरिकी नेता बहुत प्रसन्न हुए। अमेरिका को सन्तोष देने वाला एक अन्य सोवियत वायदा यह था कि संयुक्तराज्य अमेरिका की वायुसेना उस समय सोवियत सुदूरपूर्व के ग्रहों का प्रयोग कर सकती है जबकि सोवियत रूस प्रशान्त युद्ध में सम्मिलित हो जाए। यह वायदा बाद में महत्त्वहीन प्रतीत हुआ।

सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्रसंघ •

(Soviet Russia and U.N.O.)

याल्टा सम्मेलन में स्वीकार की गई दूरी योजना संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के प्रारूप की थी। इसकी अगस्त-प्रकल्प 1944 में उनके प्रतिनिधियों द्वारा डम्बर्टन ओक्स (Dumbarton Oaks) सम्मेलन में त्रियान्वित किया गया। सोवियत नेताओं

को इस प्रकार के संगठन के महत्व के सम्बन्ध में पर्याप्त शक था। वे इसे केवल अपने विचार के साधन के रूप में देखते थे। किन्तु फिर भी सोवियत नेताओं ने यह निर्णय लिया कि वे अब विश्व-राजनीति में पृथक् रहने की नीति नहीं अपनाएँगे और प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, किन्तु शर्त यह है कि उसका प्रयोग राष्ट्रमंडल की भाँति सोवियत संघ के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

सोवियत संघ को आशंका थी कि समुक्त राष्ट्रसंघ में उसका हमेशा अल्पमत रहेगा और इसीलिए उन्होंने प्रस्तावित समुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिषद् में मतदान की विशेष व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार प्रक्रिया से सम्बन्धित निर्णयों के अतिरिक्त निर्णयों को 11 सदस्यों में से 7 के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इन 7 में इसके सभी स्थायी सदस्य अर्थात् बड़ी शक्तियाँ होती चाहिए। इस एकमत सम्बन्धी चारा ने महाशक्तियों को सुरक्षा-परिषद् के निर्णयों पर निषेधाधिकार प्रदान किया। इस प्रक्रिया में पश्चिमी शक्तियाँ सोवियत रुख के विरुद्ध मत प्रयोग नहीं कर पाएँगी। इसी प्रकार सोवियत नेताओं ने प्रस्तावित समुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी मत-शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से यह माँग की कि सोवियत संघ के 16 गणराज्यों को इसमें अलग से मतधिकार प्रदान किया जाए। उनका तर्क था कि ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्यों को भी महासभा में पृथक् से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार उसके मत बढ़ जाएँगे। सोवियत संघ के इस तर्क का जवाब इस रूप में दिया गया कि इस आधार पर समुक्तराज्य अमेरिका भी अपने 48 राज्यों के लिए 48 मतों की माँग कर सकता है। ऐसी स्थिति में सोवियत रुख को दो अतिरिक्त मतों से ही सन्तोष करना पड़ा—एक यूक्रेन (Ukraine) के लोगों के लिए तथा दूसरा स्कैंडिनेविया के लिए।

याल्टा सम्मेलन को शर करने से पूर्व 'तीन बड़ों' ने सभी मित्रराष्ट्रों को तथा घुरीराष्ट्रों पर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को 1 मार्च, 1945 को सन-फ्रांसिस्को में समुक्त राष्ट्रसंघ के प्राख्य पर विचार करने के लिए एक महासम्मेलन के लिए आमन्त्रित किया।

जर्मनी का आत्मसमर्पण (The German Surrender)

सन-फ्रांसिस्को सम्मेलन (San-Francisco Conference) 25 अप्रैल से 26 जून, 1945 तक चला। इस समय तक युद्ध भी समाप्त होने को था रहा था। युद्ध के अन्तिम समय में सोवियत सेना तथा पश्चिमी सेनाओं के बीच जर्मनी पर हावी होने की दौड़ लगी हुई थी। सोवियत संघ को पूरा भय था कि जर्मनी पश्चिमी शक्तियों के साथ वार्ता करेगा अथवा वह पश्चिमी सीमा को खोल देगा और पूर्वी सीमा पर कड़ा रुख अपनाएगा। ऐसी स्थिति में पश्चिमी सेनाएँ जर्मनी पर छा जाएँगी। किन्तु यह सब नहीं हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों ने अपने सोवियत मित्र पर पूरा विश्वास रखा तथा युद्धबन्दी समझौते से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जर्मनी एक साथ सभी मित्रराष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करे।

बर्लिन के पूरे प्रयासों के बावजूद जनरल आइजनहॉवर ने अमेरिकी सेनाओं

को एलबी (Elbe) पर रोक दिया तथा जानबूझ कर बर्लिन के आधिपत्य का अवसर खो दिया। सोवियत सेनाओं ने 13 अप्रैल को वियना पर अधिकार कर लिया और 2 मई को बर्लिन उसके अधिकार में आ गया। अब केवल प्राग रह गया था। अमेरिकी सेनाएँ चेकोस्लोवाकिया में आगे बढ़ी; उसके बाद 5 मई 1945 को प्राग भी जर्मनों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। इसी समय जनरल आइजनहॉवर ने सेना को पिलसन (Pilsen) पर ही रोक दिया। चेकोस्लोवाकिया के साम्यवादियों के मतानुसार यह कदम इसलिए उठाया गया था ताकि जर्मनी के लोगों को विद्रोह दबाने के लिए समय मिल सके। सम्भवतः ऐसा ही सोवियत सेनाओं द्वारा बार्सा में किया गया था। सोवियत सेना ने प्राग को 9 मई, 1945 को स्वतन्त्र कराया। सोवियत रूस ने राजधानियों पर कब्जा करने में तथा युद्ध को समाप्त करने में पर्याप्त रुचि ली। जब जर्मनों ने आइजनहॉवर के हेडक्वार्टर में 7 मई, 1945 को उसके बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया तो सोवियत सेना ने इस बात पर जोर दिया कि यही प्रक्रिया दूसरे दिन मार्शल जॉर्ज भुकोव के सामने भी बर्लिन में दोहरायी जाए।

पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप में प्रादेशिक समझौते

(Territorial Settlement in East-Central Europe)

तीन बड़ों के बीच की एकता में दरारें जर्मन आत्मसमर्पण से पूर्व ही पड़ गई थी। सोवियत सरकार का मत था कि अपनी सेनाओं द्वारा विजित प्रदेशों के साथ वह मनमाना व्यवहार करेगी। ऐसी स्थिति में उसने पश्चिमी शक्तियों की इच्छा का ध्यान दिए बिना ही पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप के क्षेत्रीय प्रश्नों को सुलझाना प्रारम्भ किया। फ़िनलैंड तथा रूमानिया में रूस ने सन् 1944 की सन्धि द्वारा ही वांछित प्रदेश ले लिया था। 25 जुलाई, 1944 को मास्को में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की पोलिश समिति के साथ एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके द्वारा पोलिश-सोवियत सीमा विवाद सुलझाया गया। बाद में सोवियत सेना के साथ पोलिश समिति को पोलैंड भेजा गया। मई, 1945 में इसने पश्चिमी शक्तियों को पूछे बिना ही पोलैंड को ओडरनिशी पक्ति का जर्मन क्षेत्र देकर उसकी क्षतिपूर्ति कर दी।

इसके साथ ही सोवियत संघ कोनिसवर्ग तथा पूर्वी प्रशा की ओर बढ़ने लगा। चेकोस्लोवाकिया भी वैसे तो पोलैंड की भाँति एक मित्र राष्ट्र था, किन्तु उससे कहा गया कि वह स्वेच्छा से ही अपने बड़े 'स्लाव' भाइयों को प्रदेश प्रदान कर दे। 29 जून, 1944 को मास्को में एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार चेकोस्लोवाकिया ने सोवियत संघ को रूथेनिया (Ruthenia) सौंप दिया जो पहले कभी भी सोवियत-साम्राज्य का भाग नहीं रहा था। इसने फलस्वरूप सोवियत रूस और हंगरी की सीमाएँ मामान्य बन गईं तथा डनुबियन के मैदान पर उसकी शक्ति बढ़ गई। सोवियत संघ ने अपने इन पड़ोसी राज्यों को, चाहे वे औपचारिक रूप से मित्र थे अथवा शत्रु, अब अपना उपराज्य बना लिया।

सोवियत संघ ने अपने प्रदेशों की भूख मिटाने के बाद पोलैंड की क्षतिपूर्ति की तथा बल्गारिया को भी कुछ दिनाया गया और जेप के लिए उसने मुद्रा पूर्व की

सीमाओं को कायम रखा। कहा जाता है कि इससे सोवियत रूस को लगभग दो लाख वर्ग मील प्रदेश का लाभ हुआ जिसमें 22 मिलियन निवासी रहते थे। पूर्वी केन्द्रीय यूरोप के राज्यों में असमानता एवं समस्याओं के लिए पेरिस शान्ति-समझौता करने वालों को उत्तरदायी ठहराया।

युद्ध के अन्तिम दिनों में यूगोस्लाव के सैनिकों ने उस समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया जिसके बारे में प्रथम विश्वयुद्ध से ही सघर्ष चल रहा था। उन्होंने आस्ट्रिया में भी ट्रिस्टे (Trieste) तथा क्लानेनफर्ट (Klagenfurt) पर अधिकार कर लिया। ग्रेट-ब्रिटेन यह मान चुका था कि यूगोस्लाविया उसके प्रभाव से निकल गया। अब उसे इटली को बचाने की अधिक चिन्ता थी क्योंकि यहाँ साम्यवादी आन्दोलन प्रबल होता जा रहा था। ब्रिटेन के प्रोत्साहन पर अमेरिका ने शक्ति-प्रयोग द्वारा इन बन्दरगाहों से यूगोस्लाविया को पीछे हटाने की योजना बनाई। हार्पकिंस तथा स्टालिन की वार्ता के बाद 9 जून, 1945 को बेलग्रेड में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार आंग्ल-अमेरिकी तथा यूगोस्लाव सेनाओं के बीच एक विभाजक रेखा मार्गन लाइन बना दी गई। इसका अन्तिम निर्णय शान्ति-सम्मेलन के लिए छोड़ दिया गया। इस लाइन के अनुसार ट्रिस्टे तथा आस्ट्रिया के उत्तर में एक रेलरोड तो आंग्ल-अमेरिकी नियन्त्रण में रखी गई तथा पहले के अन्य इटालवी क्षेत्र यूगोस्लाविया के पास रहे।

पोट्सडाम सम्मेलन (The Potsdam Conference)

यह सम्मेलन 'बड़े तीन' का अन्तिम सम्मेलन माना जाता है जो 17 जुलाई, 1945 से 2 अगस्त, 1945 तक पोट्सडाम में चलता रहा। इस सम्मेलन में सोवियत नेताओं के लिए मुख्य प्रश्न जर्मनी तथा क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित थे। स्वतन्त्र यूरोप पर आल्ता-घोषणा-पत्र द्वारा अमेरिका ने यह प्रयास किया कि पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप का साम्यवादीकरण होने से रोका जाए, किन्तु सोवियत नेताओं ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बताया तथा इसके सम्बन्ध में पश्चिमी नेताओं को कुछ भी हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। पश्चिमी राजनीतिज्ञों ने कोलिनबर्ग पर सोवियत-अधिकार तुरन्त स्वीकार कर लिया, किन्तु पोलैण्ड की दो जाने वाली क्षतिपूर्ति का आकार कम करने पर जोर डाला। पर्याप्त विवाद के बाद वे इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय प्रश्नों को शान्ति-समझौते के अन्तिम निर्णय के लिए रखा जाए तब तक इस प्रदेश पर पोलिश सरकार का प्रशासन रहे।

जहाँ तक क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध है, सोवियत सरकार उन माँगों को दोहराती रही जो उसने आल्ता में प्रथम बार रखी थी। वह 10 मिलियन डॉलर मूल्य की क्षतिपूर्ति चाहता था, किन्तु पश्चिमी सरकारों ने पुनः इस माँग को ठुकरा दिया। सोवियत संघ ने मित्रराष्ट्रों के क्षतिपूर्ति-आयोग के सगठन की प्रतीक्षा नहीं की तथा जर्मनी पहुँचते ही उसने अपने क्षेत्र को समस्त चत-सम्पत्ति से वंचित करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया। दुर्भाग्य ने रूसी क्षेत्र कृषिप्रधान था जबकि उसे औद्योगिक सामान तथा यन्त्रों की जरूरत थी। ये चीजें जर्मनी के पश्चिमी भाग में थीं जो

ब्रिटेन के अधिकार में था। इन्होंने पर भी सोवियत सघ सौदेबाजी करने की स्थिति में था क्योंकि जर्मनी के पश्चिमी भागों को सोवियत भाग से ही अन्न आयात करना जरूरी था अन्यथा विदेशों से अन्न मगाना होना और इसका खर्चा उनको स्वयं चुकाना पड़ता। उस समय जर्मनी का खाद्यान्न-भण्डार अधिक नहीं था। इसकी अर्थव्यवस्था पर युद्ध का बुरा असर पड़ा था, इस पर भी सत्ताधारी शक्तियों की मांग का बोझ था। ऐसी स्थिति में जर्मनी क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ था। पर्याप्त वाद-विवाद के बाद तीन बड़े एक जटिल सूत्र पर सहमत हुए। इसकी मूल बात यह थी कि जर्मनी को एक आर्थिक इकाई (Economic Unit) समझा जाए। सोवियत रूस को उसके क्षेत्र में जो भी प्राप्त हुआ उसके अनतिरिक्त पश्चिमी भाग की सामान्य आवश्यकताओं से ऊपर के औद्योगिक सामान में से 10 प्रतिशत दिया जाना था। जब पश्चिमी क्षेत्र सोवियत क्षेत्र से खाद्य सामग्री तथा अन्य चीजें लेंगे तो इसके लिए वे 15 प्रतिशत और देगे। इधर पोलैण्ड भी अपनी क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा था। उसे सन्तुष्ट करने के लिए सोवियत सघ को जर्मनी के एक-तिहाई व्यापारिक पोत एवं युद्ध-पोत दिए जाने थे। इसके अनतिरिक्त जर्मनी की पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप में स्थित सम्पत्ति पर सोवियत सघ का अधिकार हो गया।

जर्मनी के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोवियत सघ एवं पश्चिमी राजनीतिज्ञ स्पष्ट नहीं थे। पोट्सडाम सम्मेलन में इस बात पर विचार ही नहीं किया गया। वे जर्मनी के राजनीतिक रूप का विकेन्द्रीकरण करके ही सन्तुष्ट हो गए। किसी केन्द्रीय सरकार की स्थापना नहीं की गई। कुछ समय तक यह कार्य मित्रराष्ट्रों की नियन्त्रण परिषद् करती रही। स्थानीय एवं राज्य-स्तर पर प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों पर आधारित स्वायत्त सरकारों कायम रखा गया। प्रशा राज्य को पहले तो अनेक राज्यों में विभाजित कर दिया गया और बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। तीन बड़े जर्मनी का विनियंत्रीकरण करने तथा जर्मन युद्ध-अपराधियों पर मुकदमा चलाने पर सहमत हो गए।

अप्रैल, 1945 में पश्चिमी शक्तियों को पूछे बिना ही सोवियत अधिनारियों ने समाजवादी नेता कार्ल रेंनर (Karl Ranner) के नेतृत्व में आस्ट्रियन सरकार के निर्माण के लिए कदम उठाए। कार्ल रेंनर सन् 1918 में आस्ट्रियन गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष था। सोवियत सघ का यह कथन आश्चर्यजनक था क्योंकि रेंनर के लेनिन के साथ सैद्धांतिक मतभेद थे तथा उसे साम्यवाद-विरोधी माना जाता था। यह पता जाना है कि उस समय आस्ट्रिया में अन्य कोई साम्यवादी था ही नहीं। आस्ट्रियन मन्त्रिमण्डल के 13 पदों में से केवल तीन पदों पर ही साम्यवादी थे। इनमें से एक को एहमन्थ्री बनाया गया तथा पुलिस उसके हाथ में सौंपी गई।

सोवियत सघ के एन तरफा कार्य से पश्चिमी शक्तियाँ नाराज हुईं तथा आस्ट्रिया की सरकार को पोट्सडाम सम्मेलन तक मान्यता प्रदान नहीं की। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि बिना में मित्रराष्ट्रों की एक नियन्त्रण-परिषद् स्थापित की जाए तथा नगर और ग्रहण को प्राधिपत्य क्षेत्रों (Occupation Zones) में बाँट

दिया जाए। इस प्रकार आस्ट्रिया में भी जर्मनी की सी स्थिति पैदा हो गई। रेनर ने इसकी तुलना करते हुए बताया कि ऐसा लगता है जैसे चार बड़े हाथी किमी छोटे नाब (डोंगी) में चढ़ गए हैं। आस्ट्रिया को क्षतिपूर्ति के भार से मुक्त कर दिया गया।

तेहरान तथा याल्टा सम्मेलनों में स्टालिन ने यालात्तागर स्ट्रेट का प्रश्न उठाया, किन्तु उस पर अधिक जोर नहीं दिया। उसने स्ट्रेट में अड्डों की मांग इन आधार पर की कि इन पर अधिकार करके ही टर्की रूम से गले लगने की स्थिति में आ जाएगा। याल्टा सम्मेलन के बाद टर्की ने यूरोपस्ट्रो के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार वह एक मित्रराष्ट्र बन गया। 20 मार्च को सोवियत सरकार ने 1925 की सोवियत-तुर्की सन्धि को रद्द कर दिया। टर्की ने इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप अपनी सेना को सक्रिय रखने हुए पश्चिमी शक्तियों से अपील की। पोट्सडाम सम्मेलन में सोवियत अधिकारियों ने स्ट्रेट के सोवियत अड्डों पर पश्चिमी स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया कि स्ट्रेट का वित्तीयीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। पर्याप्त वाद-विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि 1936 के मांटीभांक्न कन्वेंशन में संशोधन किया जाए क्योंकि यह समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इस कन्वेंशन के अनुसार टर्की को स्ट्रेट का सरभक्ष बनाया गया था।

जापान की हार (The Defeat of Japan)

पोट्सडाम सम्मेलन में तीन बड़ों ने इस बात पर विचार किया कि जापान को किस प्रकार हराया जाए। याल्टा सम्मेलन में रूस ने यह वायदा किया था कि यूरोपीय युद्ध के समाप्त होने के तीन माह बाद ही वह प्रशान्त-युद्ध में शामिल हो जाएगा। अप्रैल, 1945 में रूस ने 1941 में किए गए सोवियत-जापान समझौते रद्द कर दिये। स्टालिन ने मई-जून में जब हांपरिस से बातलाप किया तो यह शिकायत की कि चीन युद्ध में शामिल होने की उन मोहिबन शर्तों पर सहमत नहीं है जो तीन बड़ों द्वारा याल्टा सम्मेलन में स्वीकार की गई थी। जब तक चीन इनको नहीं मानेगा, तब तक रूम भी प्रशान्त-युद्ध में शामिल नहीं होगा।

चीन की सरकार ने याल्टा सम्मेलन के निर्णय का बहिष्कार कर दिया था क्योंकि इनमें चीन के हितों का ध्यान नहीं रखा गया था तथा उससे बातचीत भी नहीं की गई थी। चीन का प्रतिनिधि मण्डल जुलाई में मास्को आया। अभी उससे बात चल ही रही थी कि सोवियत नेताओं को पोट्सडाम जाना पड़ा। जाने के समय पूर्व ही उनको जापान का वह प्रार्थना-पत्र मिला जिसमें उनसे शान्ति के लिए कुछ मध्यस्थता करने को कहा गया था। इसने ऐसा प्रतीत होने लगा कि युद्ध सम्भवतः अनुमानित समय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा।

कहा जाता है कि पोट्सडाम में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने प्रथम अनुभव के सफल परीक्षण की सूचना दी थी, किन्तु सोवियत तातागाह पर इस सूचना का बहुत कम प्रभाव हुआ। यह परीक्षण 16 जुलाई, 1945 को आलामागोर्डो (Alamagordo)

में किया गया था। सम्मेलन में स्टालिन के दृष्टिकोण पर इस परीक्षण का कोई प्रभाव नहीं हुआ।

पोट्सडाम से लौटने के बाद सोवियत नेताओं ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सोवियत नेता ने 8 अगस्त, 1945 को मन्चूरिया पर आक्रमण किया। इस दिन जर्मनी के आत्मसमर्पण को ठीक तीन माह हुए थे। इसके एक सप्ताह बाद अर्थात् 14 अगस्त, 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस एक सप्ताह के युद्ध के लिए सोवियत संघ ने प्रचुर पुरस्कार प्राप्त किया।

14 अगस्त, 1945 को ही चीन के विदेश मंत्री में मास्को में एक सन्धि सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। इसमें छ. सहायक सम्मेलन भी संयुक्त थे। इनके अनुसार इन दोनों देशों ने जापान के विरुद्ध तीस वर्ष की एक सन्धि की। दोनों देशों ने एक-दूसरे की सम्प्रभुता का आदर करने का तथा एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। सोवियत सरकार ने चीन की राष्ट्रीय सरकार को नैतिक एवं भौतिक समर्थन देने का वायदा किया। रूस ने सक्रियता तथा मन्चूरिया में चीन के अधिकार को मान्यता दी तथा युद्ध के तीन माह बाद इन प्रदेशों को खाली करने का आश्वासन दिया। आर्थर बन्दरगाह चीन तथा सोवियत संघ का संयुक्त नौमैनिक झुंड बन गया। डायरेन (Dairen) को स्वतन्त्र बन्दरगाह घोषित कर दिया गया। चीनी चान्ग्युंग रेलवे को सोवियत संघ व चीन के सम्मिलित स्वामित्व एवं संयुक्त व्यवस्था के अधीन रखा गया। चीन ने बाहरी मंगोलिया की स्वतन्त्रता को मान्यता दे दी, किन्तु इसके लिए यहाँ जनमत-संग्रह किया जाना जरूरी था। 2 अक्टूबर, 1945 को प्रसारित शान्ति के घोषणा-पत्र में स्टालिन ने कहा कि पुरानी पीढ़ी के लोग 40 वर्ष से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

जापान में सोवियत संघ को काफी लाभ रहा और यूरोप तथा अन्य प्रदेशों में भी उसकी उपलब्धियाँ कम नहीं थी। पूर्वी एशिया में जारशाही जो खो चुकी थी उसे सोवियत संघ ने प्राप्त कर लिया और साथ ही यूरोप में भी उसने नए प्रदेश बढ़ा लिए। इस तरह सोवियत संघ की लगभग 4 लाख 90 हजार वर्गमील भूमि प्राप्त हो गई जिस पर लगभग 10 करोड़ व्यक्ति निवास करते थे।

रूस के पक्ष में महायुद्ध के परिणाम और महाशक्ति के रूप में

रूस का उदय : स्टालिनपुगीन विदेश-नीति

रूस ने महायुद्धजनित सभी कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना किया, आर्थिक पुनर्निर्माण के विशाल कार्यक्रम चलाए, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विस्तारवादी नीति अपनायी, ग्रीन-युद्ध को अत्यन्त तीव्र बनाकर और पश्चिमी राष्ट्रों को अपनी उग्र दृष्टि के आगे झुकाकर अपने राजनीतिज्ञ लक्ष्यों की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त किया। स्टालिन जब तक जीवित रहा, सोवियत नीति 'पश्चिम के प्रति उत्तरोत्तर शत्रुता, अमन्योग और अलगाव की ओर बढ़ती हुई सोवियत प्रभाव क्षेत्र की सुदृढ़ीकरण तथा दुराग्रहपूर्ण रही।' ¹ 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद से रूसी नेतृत्व

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की ओर झुकता चला गया और आज उसकी नीति अन्य किसी भी समय की तुलना में अधिक उदार, सहिष्णु और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की है।

1945 से 1953 की अवधि में सोवियत नीति का नियामक मार्गल स्टालिन रहा। महायुद्ध के परिणामों और महायुद्ध के बाद स्टालिन द्वारा अपनायी गई उस तथा आक्रामक नीतियों के कारण रूस अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में, 'महाशक्ति' (Super Power) के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इन परिणामों और नीतियों का अप्रतिष्ठित विन्दुओं में अध्ययन किया जा सकता है—

1. सोवियत रूस के युद्धोपरान्त उद्देश्य—द्वितीय महायुद्ध में सोवियत संघ के उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित थे। अधिकांश रूप में वे रूप के ऐतिहासिक उद्देश्य थे। प्रथम महायुद्ध के अवसर पर जारशाही रूस अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका जबकि द्वितीय महायुद्ध में साम्यवादी रूस अपने अधिकांश लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा। फलस्वरूप ऐतिहासिक दृष्टि से रूस तीन दिशाओं में विस्तार का आकांक्षी रहा था—पश्चिम की ओर यूरोप में, दक्षिण की ओर पूर्वी भूमध्य सागर के निकटवर्ती प्रदेश में तथा पूर्व में प्रशान्त महासागर की ओर। रूसी विस्तार के इस प्रत्यक्ष क्षेत्र के अनिश्चित क्षेत्रों से रूस ने यूरोप के अपने पड़ोसी देशों पर भी इस आधार पर प्रभाव जमाना चाहा है कि वह प्रायः आक्रामक रहा है। द्वितीय महायुद्ध में सोवियत रूस ने अपनी ऐतिहासिक विस्तार प्रक्रिया का अनुसरण किया और जब महायुद्ध का अन्त हुआ तो वह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुका था। 1918 में रूस को जितनी भू-भाग की हानि हुई थी उसे पुनः प्राप्त कर लिया। रूस ने अपनी सीमा में इतिहास में पहली बार सभी रूसी आबादी वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया, पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया और सुदूरपूर्व में अपनी स्थिति सुदृढ़ रखी। यह सब कुछ प्राप्त करने पर भी पूर्वी भूमध्यसागर के सम्बन्ध में रूस अपने ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

स्टालिन जब तक जीवित रहा, पश्चात्य जगत् के साथ रूस का मनमुटाव उपरत होता गया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त सोवियत नेतृत्व ने 'सह-अस्तित्व' में विश्वास प्रकट करते हुए लचीली नीति पर चलना आरम्भ कर दिया।

2. पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुता का विस्तार—महायुद्धकाल में पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देशों को लाल सेना ने जर्मन दासता से मुक्ति दिलाई थी और इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने जर्मनी के विरुद्ध छापामार सपनों का नेतृत्व किया था। युद्धोपरान्त इन देशों में राजनीतिक सत्ता भी साम्यवादियों के हाथ में आई और सोवियत रूस के लिए इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का विस्तार का मार्ग सरल हो गया। युद्ध के उपरान्त 1948 तक की तीन वर्ष की अल्पावधि में ही यूरोप के सात देश पूरी तरह 'लाल' बन गए। उसने 1947 और 1948 की सन्धियों द्वारा फिनलैंड को भी अपने नियन्त्रण में ले लिया। फिनलैंड की स्वतन्त्रता तो

कायम रही, लेकिन उसे यह बचन देना पड़ा कि वह विरोधी विदेश-नीति नहीं अपनाएगा। स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करायी और उस प्रकार सोवियत राष्ट्रीय सुरक्षा पक्ति को सुदृढ़ बनाया। इन देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के विकास के लिए भी समझौते किए गए। 1947 की 'मोलोटोव योजना' में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए उनके औद्योगीकरण पर बल दिया गया। पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी के साथ व्यापारिक सन्धियों की गई। पूर्वी यूरोप के देशों के साथ आर्थिक सहयोग की घनिष्ठ बनाने के लिए 1949 में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद् (Council for Economic Mutual Assistance : Com Con.) स्थापित की गई। यह 'कोम-कॉन' पश्चिम द्वारा स्थापित 'यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम (European Recovery Programme E R P.) की एक प्रकार से जवाबी कार्यवाही थी। सोवियत संघ में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सैनिक सन्धियां युद्धकाल में ही की जा चुकी थी। इसके बाद मार्च, 1946 से अप्रैल, 1949 तक 17 द्विपक्षीय सन्धियां की गईं। आगे चलकर मई, 1955 में इन देशों ने वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार सोवियत संघ के साथ वे देश और भी अधिक सुदृढ़ता से बंध गए।

रूस का प्रादेशिक प्रभुत्व-विस्तार वस्तुतः आश्चर्यजनक था। 1939 में रूस ने अपने क्षेत्र में लगभग 27 करोड़ 40 लाख वर्ग मील की वृद्धि कर ली और साथ ही लगभग 36 करोड़ वर्गमील क्षेत्र के साथ राज्य मास्को के समर्थक बन गए। इन देशों के अतिरिक्त अधिकृत पूर्वी जर्मनी भी रूसी सुरक्षण में ही था और वही समाजवाद के सिद्धान्तों पर आधारित शासन-प्रणाली कायम की जा चुकी थी।

3. विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार—जिस स्टालिन ने प्रथम महायुद्ध के बाद ट्रॉट्स्की के विश्व क्रान्ति के विचार का विरोध किया था, वही द्वितीय महायुद्ध के बाद इस नीति का प्रबल पोषक बन गया। साम्यवादी क्रान्ति को दूसरे देशों में फैलाने के लिए स्टालिन के नेतृत्व में रूस ने विभिन्न उपायों का सहारा लिया। युवान के यह-युद्ध में युवानों साम्यवादियों को पड़ोसी साम्यवादी देशों के माध्यम से सहायता पहुँचाई गई। तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) के विश्वव्यापी क्रान्तिकारी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए 1947 में विभिन्न देशों में साम्यवादी पार्टियों के नेताओं ने वेनिस में 'कामिनिस्म' की स्थापना की। इनका उद्देश्य विश्वव्यापी साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व करना था। स्टालिन चाहता था कि पूर्व और पश्चिम में रूसी साम्राज्य का विस्तार हो, रूसी सीमाओं पर रूस समर्थक राज्यों की सरकारें स्थापित हो और पुराने बुर्जुआ साम्राज्य नष्ट हो। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर स्टालिन ने विश्व समझौतों के समाधान में समझौतावादी नीति न अपनाता ही उचित मर्यादा। यह आश्चर्यजनक की नीति पर चलकर क्रान्ति-व्यवस्था की टाटना चाहता था ताकि संसार की स्थिति सोवियत संघ के लिए और भी अनुकूल हो जाए।

4. टर्की, ईरान, यूनान और यूगोस्लाविया पर सोवियत दबाव—स्टालिन काल में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के पारस्परिक सम्बन्धों में जहाँ हर प्रकार से सफलता का पलड़ा रूस के पक्ष में भारी रहा, वहाँ रूस को टर्की, ईरान, यूनान और यूगोस्लाविया के सम्बन्ध में असफलताओं का सामना करना पड़ा। सोवियत दबाव की नीति अन्ततोगत्वा सफल नहीं हो सकी। दक्षिण से होने वाले आक्रमण के विरुद्ध सोवियत सुरक्षा की मुख्य समस्या बासफोरस और डार्डेनेलीज के जलडमरूमध्य पर नियन्त्रण की थी। युद्धकाल में रूस ने इस जलडमरूमध्य की संयुक्त सुरक्षा के लिए टर्की से सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति चाही, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी पीठ पर देखकर टर्की ने सोवियत माँग ठुकरा दी। युद्ध के उपरान्त जब 'शीत-युद्ध' आरम्भ हुआ तो पश्चिमी राष्ट्रों ने दृढ़ता से टर्की का समर्थन किया। अक्टूबर, 1946 में सोवियत टर्की समझौता वार्ता भंग हो गई, पर टर्की रूसी दबाव को झेल गया।

ईरान में भी सोवियत नीति इसी प्रकार असफल रही। 1941 में रूस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने ईरान पर अधिकार कर लिया था। युद्धोपरान्त 1946 के आरम्भ में अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने ईरान खाली कर दिया, लेकिन सोवियत सेना डटी रही। मामला सुरक्षा परिषद में गया। प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा 24 मार्च, 1946 को एक समझौता हुआ जिनमें रूस ने उत्तरी ईरान में तेल सम्बन्धी रियायत प्रान्त की और अपने सैनिकों को ईरान से हटाना मजूर कर लिया। इसके बाद ही मिनस्कर, 1947 में ईरानी संसद ने सोवियत रूस को दी गई तेल सम्बन्धी रियायत के लिए स्वीकृति देना अस्वीकार कर दिया। ईरान में रूसी हस्तक्षेप का खतरा पैदा हो गया, लेकिन अमेरिका ने 'ट्रूमैन सिद्धान्त' के अनुसार ईरान को सैनिक सहायता देने और ईरानी सेना को संगठित करने के लिए सैनिक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का वचन दिया। फलस्वरूप ईरान में रूसी हस्तक्षेप का संकट टल गया।

यूनान में भी एक नाम्यवादी शासन की स्थापना के रूसी प्रयत्न असफल रहे। 1944 में चर्चिल और स्टालिन ने मास्को में यह स्वीकार किया था कि यूनान ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद मित्रराष्ट्रों का सहयोग टूट गया। मई, 1946 में साम्यवादियों ने पूरी शक्ति से गृह-युद्ध छेड़ दिया और अमेरिका ने 'ट्रूमैन सिद्धान्त' के अन्तर्गत यूनान को मदद देने का निश्चय कर लिया। धीरे-धीरे एंसेस सरकार ने अमेरिकी सरकार की सहायता से अपनी सेना को सुसज्जित कर लिया और अक्टूबर, 1949 में साम्यवादी आन्दोलन समाप्त हो गया। रूस को सबसे अधिक असफलता यूगोस्लाविया के मामले में हाथ लगी, क्योंकि कुछ समय तक रूसी गुट में बने रहने के बाद यूगोस्लावी राष्ट्रपति टीटो ने रूस के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और जून, 1948 में यूगोस्लाविया रूसी गुट से पृथक् हो गया। मार्शल टीटो पर स्टालिन ने हर प्रकार से दबाव डालने की कोशिश की, किन्तु वह टीटो को अपने कब्जे में नहीं ला सका। टीटो को यह

कनई पसन्द नहीं था कि यूगोस्लाविया स्थित लाल सेना यूगोस्लाविया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, अतः उसने स्टालिन से स्पष्ट शब्दों में माँग की कि रूसी फौजें यूगोस्लावी क्षेत्र से हटा ली जाएँ। स्टालिन और टीटो के मतभेद बढ़ते गए। 28 जून, 1948 को 'कोमिनफोर्म' (Communist Information Bureau : Cominform) ने यूगोस्लाव साम्यवादी पार्टी पर यह आरोप लगाकर उसे अपनी सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया कि उसकी नीतियाँ मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के सिद्धान्तों के प्रतिवृत्त हैं। यूगोस्लाव नेताओं ने कोमिनफोर्म द्वारा लगाए गए आरोपों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सोवियत संघ और यूगोस्लाविया के बीच शीतयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई जो स्टालिन की मृत्युपर्यन्त (मार्च 1953) चलती रही। टीटो के इस विद्रोह का पश्चिमी देशों ने स्वभावतः मुक्त कण्ठ से स्वागत किया। मार्शल टीटो ने, सोवियत रूस से धुंध होकर, पूर्वी यूरोप के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अपेक्षा पश्चिमी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना शुरू कर दिया, किन्तु यह सदैव ध्यान रखा कि उनका राष्ट्र पूर्णतः एक स्वतन्त्र राष्ट्र रहे जो सोवियत या पश्चिमी प्रभाव से मुक्त अवस्था का उपभोग करे।

5 पश्चिम का विरोध और शीत-युद्ध की तीव्रता—सोवियत रूस की पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना के प्रयत्नों और पश्चिमी शक्तियों द्वारा रूसी प्रभाव के प्रसार को रोकने की चेष्टाओं के कारण सोवियत संघ और पश्चिम की 'विचित्र मैत्री' का अन्त हो गया तथा युद्ध समाप्त होने के तीन वर्ष के अन्दर ही दोनों गुटों में गम्भीर शीतयुद्ध प्रारम्भ हो गया। जर्मनी, आस्ट्रिया, टटली आदि शत्रु राज्यों के साथ सन्धियों की शर्तों, इटली के उपनिवेशों का तथा राष्ट्रसंघ के मेम्बर वाले प्रदेशों का विभाजन, स्वतन्त्रता, जर्मनी के निःशस्त्रीकरण और एकीकरण की समस्या, पश्चिमी देशों तथा रूस के और लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों का मौलिक अन्तर, क्षतिपूर्ति, मध्यपूर्व में प्रभुता पाने के लिए तीव्र प्रतियोगिता आदि ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हुईं जिन पर दोनों पक्षों में उग्र मतभेद उजागर हुए जिनके फलस्वरूप शीत-युद्ध की तीव्रता बढ़ी। जहाँ पश्चिमी राष्ट्र कोमिनफोर्म की गतिविधियों और रूसी प्रभाव के प्रयासों व स्टालिन की अदम्य नृत्नीतिक चालों और हठधर्मी आदि से आशङ्कित और अस्त थे, वहाँ सोवियत संघ के इस विश्वास को सम्बल मिला कि पश्चिमी राष्ट्र उसके सम्मूलन का पङ्कज करने में लगे हुए हैं। रूस की दृष्टि टूमैन सिद्धान्त, मार्शल योजना, बर्लिन के घेरे के समय दी गई हवाई सहायता, जापान व जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण प्रूमेन एवं प्लेवन योजनाएँ, कोरिया युद्ध आदि पश्चिमी राष्ट्रों के ऐसे कार्य थे जो रूस के प्रति पश्चिम के विशेषकर अमेरिका के घोर विरोध और उनकी उग्र शत्रुता के प्रमाण बहते जा सकते थे। आणविक शक्ति से सम्पन्न मयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गुट की दन कार्यवाहियों से स्टालिन की आशङ्काएँ उत्तरोत्तर बढ़ती गईं और वह पश्चिम की प्रत्येक कार्यवाही तथा गतिविधि का विरोध करने लगा।

यद्यपि स्टालिन पश्चिम के प्रति अपनी नीति को शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व (Peaceful Co-existence) का जामा पहनाता था, परन्तु उसके कार्य-कलापों से यह स्पष्ट हो गया कि 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व' की इस नीति से उसका अभिप्राय केवल इतना था कि दोनों पक्षों में सशस्त्र युद्ध नहीं होना चाहिए। एक प्रकारात्मक वाक्युद्ध और कोरिया जैसे स्थानीय युद्धों को वह इस नीति के विरुद्ध नहीं समझता था। स्टालिन की इस नीति का एक अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि वह धीरे-धीरे पश्चिम और साम्यवादी शक्तियों का शीतयुद्ध तीव्रतर होना चला गया।

6. सोहू आवरण की नीति—स्टालिन को भय था कि यदि पाश्चात्य लोकतन्त्र के जीवाणु सोवियत संघ में प्रवेश कर गए तो साम्यवादी शासन के लिए एक अशुभ बात होगी। इसीलिए उसने सोहू-आवरण की नीति अपनायी ताकि रूस को सभी प्रकार के पश्चिमी प्रभावों से अछूता रखा जा सके। महायुद्ध के तुरन्त बाद समुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी राज्यों ने साम्यवाद के विरुद्ध जोर-शोर से जहरीला प्रचार शुरू कर दिया। साम्यवादी देशों के इर्द-गिर्द अज्ञान रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए जिनके नाम 'आजाद हंगरी रेडियो', 'आजाद पोलैण्ड रेडियो' आदि रहे गए किन्तु स्टालिन भी पूरा 'घाघ' था। उसने विभिन्न प्रतिबन्ध लगाकर साम्यवादी जगत् के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि साम्यवाद-विरोधी प्रचार प्रवेश न कर सके। स्टालिन ने इस ओर पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को गैर-साम्यवादी देशों के सम्पर्क से वृथक रखने का निश्चय कर लिया। कठोर कानूनों द्वारा 1945 से ही रूमियों का बाह्य जगत् के साथ सम्पर्क रोक दिया गया। उदाहरणार्थ, एक कानून द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि युद्ध के समय रूस में आए हुए विदेशी सैनिकों के साथ जिन रूसी स्त्रियों ने विवाह किया था वे अपने पतियों के पास विदेश नहीं जा सकेंगी। एक अन्य कानून द्वारा विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाहों पर रोक लगा दी गयी। विदेशी राजदूतों और पत्र-प्रतिनिधियों के साथ भी बहुत कठोरता का व्यवहार किया गया। विदेशों में स्थित सोवियत राजदूतों पर भी कठोर अनुशासनात्मक प्रतिबन्ध लगाए गए।

7. शान्तिवादी आन्दोलन की कूटनीति—सोवियत रूस के पक्ष एशिया और अफ्रीका समर्थन प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ ने युद्ध के कुछ समय ही बाद 'शान्ति-आन्दोलन' (Peace Offensive) प्रारम्भ किया। पूँजीवादी पश्चिम को 'युद्ध-खोलुप' (War-Monger) कहा गया। 1950 में स्टॉकहोम विश्वशान्ति सम्मिति द्वारा आणविक आयुधों पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगाने की अपील पर उच्चिन्तन समय पर लगभग 50 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त कराए गए। इस शान्ति आन्दोलन ने एशिया और अफ्रीका की विशाल जनसंख्या को बहुत प्रभावित किया। वे साम्यवाद की ओर आकर्षित होने लगे तथा सोवियत संघ को पश्चिम की तुलना में अधिक शान्तिप्रिय और साम्राज्य विरोधी मानने लगे। साम्यवादियों ने इन आन्दोलन में सब देशों के मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों से सहयोग माँगा। जहाजी श्रमिकों में यह प्रचार किया गया कि अमेरिका से शरणास्थों को लाने वाले जहाजों

से माल न उतारा जाए और हड़ताल कर दी जाए। प्रचार की दृष्टि से शान्तिवादी आन्दोलन को प्रारम्भ करने में पर्याप्त सफलता हुई। यद्यपि स्टालिन अपने अनुदार दृष्टिकोण के कारण इस आन्दोलन से रूस को अधिक लाभान्वित नहीं कर सका, तथापि विश्व के देशों में रूसी शक्ति और रूसी क्षमता की चर्चा होने लगी। पश्चिमी देश भी यह समझ गए कि यदि पूँजीवादी गुट में अमेरिका जैसी महाशक्ति है तो साम्यवादी गुट में रूस जैसी महाशक्ति है जो अमेरिका से टक्कर लेने में सक्षम है।

8 रूस द्वारा विनाश के धावों की धो डालना—रूस ने महायुद्ध के फोड़ों को थोड़े ही समय में आश्चर्यजनक रूप में मलहम पट्टी कर ली। रूसी नागरिकों में आत्म-विश्वास का अभूतपूर्व प्रादुर्भाव हुआ। रूस ने समाजवादी पद्धति के कारण, द्रुत गति से अपना पुनर्निर्माण कर लिया और नाजी आक्रमण की कड़वी स्मृतियों को मिटा डाला। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी रूसी सेना में कोई विशेष कमी नहीं की गयी, इसके विपरीत आधुनिकतम शस्त्रास्त्र बनाने पर विशाल धनराशि व्यय की गयी।

9. अणु-शक्ति पर अमेरिका के स्वामित्व को भंग करना—सैनिक स्तर पर सच्चे अर्थों में एक महाशक्ति बनाने के लिए यह आवश्यक था कि रूस भी अमेरिका के समान अणु शक्ति का स्वामी बनता। रूस ने इस दिशा में प्राणपण से चेष्टा की और अगस्त 1953 में अपना प्रथम आणविक विस्फोट किया। इससे रूस की प्रतिष्ठा में चार चाँद लग गए तथा उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी माना जाने लगा। रूस ने अल्पकाल में ही विभिन्न प्रकार के अणु आयुधों और अणुबमों का निर्माण कर अमेरिका के लिए गम्भीर चुनौती प्रस्तुत कर दी।

10 संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति सोवियत नीति—स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में सक्रिय भाग लिया। दुर्भाग्यवश अपने जन्मकाल के कुछ ही समय पश्चात् संघ शीत-युद्ध का प्रधान खिलाड़ा बन गया। लगभग प्रत्येक समस्या पर दोनों राष्ट्र अथवा दोनों गुट दो विरोधी दृष्टिकोण लेकर संघ के मंच पर उपस्थित हुए। चूँकि संघ में पश्चिमी शक्तियों और उनके समर्थकों का स्फुट बहुमन था अतः सोवियत रूस ने स्वयं को स्थायी एवं निरन्तर अल्पमत में पाया। ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा के प्रतिबल होने वाले निर्णयों को रोकने के लिए उसके पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय न था कि वह सुरक्षा परिषद में अपने निषेधाधिकार का खुलकर प्रयोग करे जिससे संयुक्त राष्ट्रसंघ पश्चिमी शक्तियों के इशारों पर उनके पक्ष में कोई प्रभावशाली कार्य न कर सके। कोरिया-युद्ध के समय अल्पकाल के लिए रूस ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की बैठकों का बहिष्कार कर दिया। लेकिन यह बहिष्कार उसके लिए पाटे का सौदा मिट्ट हुआ क्योंकि इस बहिष्कार के कारण ही संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए भेजी जा सकीं। रूस ने यह समझ लिया कि वह संयुक्त राष्ट्रसंघ से बाहर रहने की अपेक्षा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेकर, परिषद की बैठकों में उपस्थित होकर, पश्चिमी राष्ट्रों के इशारों पर अधिक प्रभावी रूप से रोक लगा सकता है।

मूल्यांकन

वास्तव में स्टालिन ने मृत्युपर्यन्त एक आक्रमणकारी, गतिशील, अडगनेवाजी और लोह धावरण तथा समझौता-विरोधी नीति का अनुसरण किया। पूर्वी यूरोप में अपने वचनों को झुठलाकर सोवियत प्रभुत्व का विस्तार किया गया, यूनान के गृह युद्ध में साम्यवादियों की सहायता की गयी, टर्की पर बासफोरस तथा डार्डेनेलीज के जलडमरूमध्यों के सम्बन्ध में माण्ट्रेबस (Montreaux) के समझौते को बदलने के लिए दबाव डाला गया, मार्शल-योजना की सहायता लेना अस्वीकार कर दिया गया। ईरान से सोवियत सेनाओं के हटाने में देर लगायी गई, टोटी को मास्को के गुट से निष्कासित किया गया, कोरिया व हिन्द चीन में युद्ध हुए। स्टालिन की इस आक्रामक नीति से पश्चिमी शक्तियाँ सशक्त हो गईं और उन्होंने बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को रोकने तथा साम्यवाद के प्रसार के विरोध के लिए अनेक उपाय किए। ट्रूमैन सिद्धान्त, मार्शल योजना, डकक-थूसेल्स सन्धियाँ, नाटो पैक्ट, पश्चिमी यूरोप की एकता के लिए बनाए गए विभिन्न समूह आदि स्टालिन की कठोर नीति के प्रभावशाली प्रत्युत्तर थे। 1945-47 तक यूरोप की स्थिति स्टालिन के लिए बड़ी अनुकूल थी, लेकिन 1953 तक स्थिति ऐसी नहीं रही। मध्यपूर्व में टर्की और यूनान में हस्तक्षेप के कारण सोवियत रूस की वैसी बदनामी हुई जैसी बाद में शाइजनहावर सिद्धान्त के प्रयोग से अमेरिका की हुई। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति भी स्टालिन की नीति अनुदार रही। इससे उसने एक बड़ी सीमा तक इन राष्ट्रों का समर्थन खो दिया। तटस्थ देशों के प्रति स्टालिन ने विरोधी नीति का अनुसरण किया। उदाहरणार्थ, भारत को उसकी तटस्थता के कारण ही स्टालिन रूस-विरोधी समझता रहा। स्टालिन की उग्रवादी कठोर नीति ने स्वयं साम्यवादी गुट में काफी क्षोभ उत्पन्न कर दिया।

द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में दो महाशक्तियों का उदय हुआ—संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। विश्व में शक्ति के दो प्रमुख केन्द्र उभर कर सामने आए और लगभग 1954-55 तक विश्व में दृढ़-द्वि-ध्रुवीयता (Tight Bipolarity) का बोलबाला रहा। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे की जबर्दस्त प्रतियोगी बन गयीं और दोनों ही के नेतृत्व में दो विरोधी गुटों का निर्माण होता गया। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा विशेष कर यूरोप में बहुत तीव्र रही जिससे न केवल शीतयुद्ध में तीव्रता आयी बल्कि प्रतिद्वन्द्वी सन्धियों और अनेक सैनिक गुटों का निर्माण भी होनी से हुआ। 1955 के प्रारम्भ में स्थिति यह थी कि नहीं विश्व शक्ति और संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता केवल 59 सम्प्रभु राज्यों तक सीमित थी वहीं अमेरिका और ब्रिटेन एक ओर तथा रूस और अन्य राष्ट्र दूसरी ओर लगभग 60 से भी अधिक राज्यों के साथ बँधे थे। 1955 के मध्य द्वि-ध्रुवीयता शिथिल होने लगी और धारा बहुकेन्द्रवाद (Poly-centr.cism) की ओर बहने लगी। आज यद्यपि शक्ति के अनेक केन्द्र कम से कम चार या पाँच उभर आए हैं फिर भी महाशक्तियों के रूप में वस्तुतः अमेरिका और रूस की ही गणना की जाती है। निकट भविष्य में साम्यवादी चीन और भारत भी महाशक्तियों का दर्जा पा सकेंगे, इसकी सम्भावनाएँ प्रबल हैं।

मोलेन्कोव काल (1953-1954)

स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और वह फिर से विकासोन्मुख बनी। स्टालिन के बाद तीन मुख्य बातों ने सोवियत संघ की शक्ति को बढ़ा दिया। पहली बात यह थी कि पूर्वी-यूरोप में सोवियत साम्राज्य में स्थायित्व आ गया। दूसरे सोवियत संघ की आर्थिक तथा सैनिक शक्ति तेजी के साथ बढ़ने लगी। तीसरे, रूस के दक्षिणी क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। मध्यपूर्व दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश उसके प्रभाव-क्षेत्र में आ गए। विश्व का सन्तुलन एक प्रकार से साम्यवाद की ओर झुक गया। स्टालिन के बाद यद्यपि सोवियत साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ, तथापि सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी प्रभावशाली हो गई कि पहले कभी नहीं थी।

स्टालिन के उत्तराधिकारियों को जिन चुनौतियों का सामना करना था, वे थी—सोवियत साम्राज्य की रक्षा करना, पूर्वी यूरोप में सोवियत शासन के स्थायित्व पर पाश्चात्य मान्यता प्राप्त करना तथा जहाँ सम्भव हो सके वहाँ बिना सोवियत सुरक्षा को खतरे में डाले देश की शक्ति का विस्तार करना। एक साम्राज्य की रक्षा करना उसे प्राप्त करने से अधिक कठिन होता है, इसलिए साम्राज्यान्तर्गत प्रदेशों को स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की गई, आर्थिक सम्बन्धों को कम शोषणयुक्त बनाया गया तथा जीवन-स्तर के विकास को प्रोत्साहन दिया गया।

स्टालिन की उप्रतावादी कठोर वंदेशिक-नीति के जो परिणाम निकले और पाश्चात्य देशों एवं तटस्थ देशों में उसकी जो प्रतिक्रियाएँ हुईं, उनके फलस्वरूप अब सोवियत नीति का एक नवीन दिशा में उन्मुख होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य था। इसलिए स्टालिन के अविलम्ब उत्तराधिकारी मोलेन्कोव ने दिवंगत नेता के अन्त्येष्टि सस्कार में ही घोषणा की कि—“लेनिन और स्टालिन की शिक्षाओं के अनुसार साम्यवादी तथा पूँजीपति देशों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया जाएगा।” 15 मार्च, 1953 को सुप्रीम सोवियत में अपने देश की विदेश नीति का उल्लेख करते हुए सोवियत प्रधान मंत्री ने जोरदार शब्दों में कहा—“अब सोवियत विदेश-नीति का संचालन व्यापार की वृद्धि और शान्ति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से किया जाएगा। कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसका शान्तिपूर्वक हल नहीं किया जा सकता हो। यह सिद्धान्त सयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के सब देशों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू होता है।”

रूस की इस नई विदेश-नीति के सुखद परिणाम भी शीघ्र ही निबलने प्रारम्भ हो गए। अक्टूबर, 1952 से चले आने वाले कोरियाई युद्ध का गतिरोध खत्म हो गया और 10 अप्रैल, 1953 को पानमुनजोन में रण एवं घायल युद्ध-बन्धियों का सम्भोग होने पर युद्ध भी समाप्त हो गया। रूस द्वारा टर्की और जर्मनी के प्रति उदार नीति अपनाई गई। 15 मई, 1955 को ब्रास्ट्रुया के सम्बन्ध में शान्ति सन्धि हो गई। सोवियत सैनिकों द्वारा फिनलैंड के सैनिक छड़्डे वाली कर दिए गए।

1954 में जेनेवा-सम्मेलन द्वारा हिन्द-चीन की समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकाला गया। सोवियत-संघ ने पूनान और इजरायल के साथ पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। यूगोस्लाविया के साथ मतभेदों को दूर करके उसे पुनः साम्यवादी परिवार में लाने की चेष्टा की गई। मई, 1953 में दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक सम्बन्ध फिर से वायम हो गए।

मोलेन्कोव के नेतृत्व में सोवियत रूसी लोह आचरण के सम्बन्ध में भी शिथिलता की नीति चरती जाने लगी। बाह्य दुनिया से निकट सम्पर्क वायम करने का प्रयास किया गया ताकि सोवियत संघ लोहे की दीवार में बन्द न समझा जाए। स्टालिन विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित मानता था, लेकिन नई नीति के अनुसार इसको शक्ति-सन्तुलन की प्रक्रिया माना गया और इसे अपने पक्ष में करने के लिए तटस्थ राष्ट्रों की सद्भावना प्राप्त करने की चेष्टा की गई।

खुश्चेव-काल (1955-1964)

इस समय सोवियत संघ में भीतर ही भीतर नेतृत्व के लिए सघर्ष चल रहा था। मोलेन्कोव इस सघर्ष में पराजित हुए, फलतः 8 फरवरी, 1955 को उन्हें प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अब मार्शल बुल्गानिन नए सोवियत प्रधान मंत्री बने तथा खुश्चेव पार्टी के महासचिव नियुक्त हुए। 1955 से 1963 तक की सोवियत विदेश-नीति का युग खुश्चेव युग था क्योंकि फरवरी, 1955 से मार्च, 1958 तक के बुल्गानिन प्रधानमन्त्रित्व काल में भी वास्तविक प्रभाव एक प्रकार से खुश्चेव का ही रहा।

खुश्चेवकालीन विदेश नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ

(1) लोह आचरण की नीति उत्तरोत्तर शिथिल होती गई तथा 'शान्ति-कूटनीति' का महत्त्व बढ़ता गया।

(2) पश्चिम के प्रति उग्र नीति का जर्न-जर्न परिवर्तन किया जाने लगा। सोवियत नेता शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की ओर अग्रसर हुए। विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा, पर शीतयुद्ध का परिवर्तन नहीं किया गया। अनुकूल परिस्थितियों में शीतयुद्ध को उभार कर राजनीतिक और प्रचारात्मक लाभों को प्राप्त करने के प्रयत्न चलते रहे।

(3) अल्पविकसित देशों को आर्थिक, प्राविधिक और सैनिक सहायता देने की नीति अपनाई गई। इसमें उत्तरोत्तर विकास होता चला गया।

(4) सोवियत प्रभाव-विस्तार की उत्कठा रहते हुए भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी प्रचार को तीव्र कर दिया गया। सोवियत नीति यह रही कि एशिया और अफ्रीका की जनता की अधिकाधिक सहानुभूति प्राप्त कर इन महाद्वीपों में साम्यवाद के प्रसार के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। सोवियत शक्ति और प्रभाव-विस्तार के मुख्य आकर्षण केन्द्र तीन क्षेत्र रहे—एशिया, अफ्रीका और संदिग्ध अमेरिका।

(5) अणु आयुधों में अमेरिका से समानता तथा उससे आगे निकल जाने के प्रयत्न अनवरत चलते रहे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी रणनीति रची गई।

(1) लौह आवरण में शिथिलता, यात्राओं की कूटनीति

इस युग में सोवियत लौह आवरण की नीति में पर्याप्त शिथिलता आई और 'यात्रा कूटनीति' का महत्त्व बढ़ा। सोवियत संघ के विभिन्न सांस्कृतिक तथा ससदीय शिष्टमण्डल विदेशों में जाने लगे और विदेशों के ऐसे ही शिष्टमण्डल साम्यवादी देशों में आमन्त्रित किए जाने लगे। 1955 में नेहरू तथा बुल्गानिन की परस्परयात्राओं से दोनों देशों में सद्भाव और मैत्री की वृद्धि हुई तथा सोवियत नेताओं को गुट-निरपेक्षता की नीति के प्रति स्टालिनकाल से भारत के प्रति जो सन्देह बना हुआ था वह दूर हो गया। 1956 में दोनों नेता ग्रेट ब्रिटेन गए। 1959 के आरम्भ में प्रथम सोवियत उप-प्रधानमंत्री मिर्कोयान ने अमेरिका की यात्रा की। सोवियत उप-प्रधान मंत्री ने दोनों देशों में व्यापार-वृद्धि को आवश्यक बताया और इस बात पर बल दिया कि 'शीतयुद्ध' (Cold-war) का स्थान 'शान्तिपूर्ण-प्रतियोगिता' (Peaceful Competition) को लेना चाहिए। सितम्बर, 1959 में सोवियत प्रधानमंत्री रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। फरवरी-मार्च, 1960 में रुश्चेव ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों—भारत, बर्मा, इण्डोनेशिया, अफगानिस्तान आदि की यात्रा की। अपनी यात्राओं में रूसी नेताओं ने शासनाध्यक्षों के शिखर-सम्मेलन आयोजित करने पर बार-बार बल दिया।

(2) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटारा करने की नीति

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का शुभारम्भ मोलॉटोव के प्रधानमन्त्रित्व काल में ही हो चुका था, किन्तु इसमें निखार रुश्चेव तथा इसके परवर्ती युग में आया। फरवरी 1956 में रूसी साम्राज्य दल की 20वीं कांग्रेस ने जो विदेश नीति अंगीकृत की उसकी निम्नलिखित पाँच प्रमुख विशेषताएँ थी—

प्रथम, जहाँ स्टालिन के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का अर्थ केवल युद्ध का न होना माना था, वहाँ रुश्चेव ने इसका अर्थ यह माना कि सभी गैर-साम्यवादी राष्ट्र (विशेषतः एशिया और अफ्रीका के तटस्थ राष्ट्र) सोवियत संघ के शत्रु नहीं हैं।

दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया।

तीसरे, यात्राओं की कूटनीति स्वीकार की गई और यह स्वीकार किया गया कि दूगरे देशों से अच्छे सम्बन्धों की स्थापना करने के लिए सोवियत नेताओं को अन्य देशों की यात्राएँ करनी चाहिए तथा लौह आवरण को शिथिल कर साम्यवादी एवं गैर-साम्यवादी देशों के मध्य सम्पर्क की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए।

चौथे, सोवियत संघ द्वारा विश्व के अल्प-विरामित देशों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता अनुभव की गई।

पाँचवें, पश्चिमी शक्तियों को साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी बताकर उनकी निन्दा करते हुए भी उनके साथ खुले संपर्क की नीति का परिष्कार किया गया।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नवीन सोवियत नीति के अनुसार गैर-साम्यवादी देशों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है—(1) संयुक्त राज्य अमेरिका, (2) अमेरिका के समर्थक और सहयोगी देश के, एवं (3) तटस्थ देश, जैसे—भारत, इण्डोनेशिया, बर्मा, मिस्र, सीरिया, यूगोस्लाविया, अफगानिस्तान व स्विट्जरलैण्ड। हमारे शब्दों में पहले रूस दुनिया में दो रंग के रूप देखता था—लाल और सफेद। अब वह इसमें लाल, पीले, नीले, हरे, विभिन्न प्रकार के फूल देखने लगा। पहले उसकी नीति लाल रंग के फूलों के सिवाय सब तरह के फूलों के समूलोन्मूलन की थी। अब वह सबके साथ-साथ रहने के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करने लगा। रूसी विदेश-नीति में एक निश्चित लचीलापन आया। शान्तिपूर्ण समाधान और सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को मानने के निश्चिन प्रमाण भी सोवियत रूस ने प्रस्तुत किए। उदाहरणार्थ, जुलाई, 1953 को कोरिया युद्ध की समाप्ति में रूसी सहयोग प्राप्त हुआ, जनवरी-फरवरी, 1954 में चार बड़ों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसके निश्चय के अनुसार अप्रैल में जो जेनेवा सम्मेलन हुआ, उसमें विघटन का समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। 15 मई, 1955 को आस्ट्रिया के साथ शान्ति स्थापित हुई। जुलाई, 1955 में चार बड़ों का शिखर सम्मेलन हुआ जो 1945 के पोर्ट्सहाम सम्मेलन के बाद चार बड़ों की पहली बैठक थी। इसमें हिन्द चीन के प्रश्न का शान्तिपूर्ण समाधान हुआ। इसी बीच 15 जून, 1954 को सोवियत संघ ने काले सागर के प्रदेश में टर्की के विरुद्ध अपनी प्रादेशिक मांगों का परिष्कार करने की घोषणा की।

रूसी सहयोग पाकर संयुक्त राष्ट्र मध्य अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य करने लगा। नवम्बर-दिसम्बर, 1955 में एक तरफ सोवियत रूस ने और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह निश्चय किया कि वे एक-दूसरे के द्वारा प्रस्तावित राज्यों की संयुक्त राष्ट्र मध्य का सदस्य बनाने के प्रस्तावों का विरोध नहीं करेंगे। इस निश्चय के परिणामस्वरूप 8 दिसम्बर, 1955 को 18 राज्यों की संयुक्त राष्ट्रमध्य की सदस्यता प्रदान की गई। सोवियत नेताओं ने दूसरे देशों की सद्भावना याथाएँ करना शुरू किया। 18 अप्रैल, 1956 को कोमिनफोर्म को भंग कर दिया गया। जुलाई-अगस्त 1963 में अणु-गरीक्षण-प्रतिबन्ध-सन्धि सम्पन्न की गई जिसे 1922 की वाशिंगटन मन्त्रियों के पश्चात् निःशस्त्रीकरण के प्रयत्नों की प्रथम सफलता कहा जा सकता है। अगस्त में ही मास्को और वाशिंगटन के मध्य सीधा टेलीफोन तथा रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता (U S. Soviet Hot Line Agreement) किया गया।

ए.श्वेव काल में 'पूर्व' और 'पश्चिम' के सम्बन्धों में निश्चित रूप से सुधार हुआ, किन्तु राजनीतिक जगत् के रूप में दोनों की स्थिति यथापूर्व रही और कूटनीतिक पावरप्ले द्वारा अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में दोनों ही पक्ष अग्रसर रहे।

मौके-बेमौके ऐसे अवसर उपस्थित होते रहे और ऐसी घटनाएँ घटी जिनसे समय-समय पर शीत-युद्ध की तीव्रता दिखाई दी और दोनों पक्षों में कटुता का व्यापक प्रसार हुआ, उदाहरणार्थ 1956 में स्वेज नहर और हंगरी के प्रश्न पर दोनों पक्षों में अत्यधिक कटुता उत्पन्न हो गई, मई 1960 में यू-2 विमान की घटना ने दोनों पक्षों में शीत-युद्ध का ग्यार ला दिया और 1962 में क्यूबा के संकट ने दोनों महाशक्तियों को सघर्ष के इतने निकट ला दिया कि तृतीय महायुद्ध के विस्फोट की सम्भावना से विश्व की सम्पूर्ण शान्तिवादी जनता चौकन्नी हो गई।

(3) अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग

मॉलेंकोव और ह्यूश्चेव युग में सोवियत संघ ने भी अल्प-विकसित देशों को आर्थिक, प्राविधिक और सैनिक सहायता देने की नीति अपनायी जो आज तक सोवियत विदेश-नीति का एक प्रमुख अंग बनी हुई है। साथ ही सोवियत रूस ने उत्पादन और सैनिक शक्ति में स्वयं को पश्चिमी देशों से थोड़ातर सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास किया। 1957 में स्पूतनिक और 1961 में 50 मेगावाट बम का निर्माण कर वह रकेटों तथा आणविक शस्त्रों की दौड़ में संयुक्त राज्य से भी आगे निकल गया।

(4) उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध

ह्यूश्चेव ने एशिया और अफ्रीका के देशों तथा असलमन विश्व (Uncommitted World) की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी प्रचार को भी तीव्र कर दिया। उपनिवेशों तथा गुलाम राष्ट्रों को स्वतन्त्र बनाने के सभी प्रस्तावों और आन्दोलनों को प्रबल समर्थन दिया जाने लगा। ह्यूश्चेव के प्रभाव में आने के उपरान्त से, एशिया और अफ्रीका के अल्प-विकसित या अविकसित देशों और उपनिवेशों के प्रति सोवियत नीति के निम्नलिखित प्रमुख तथ्य थे—

- (i) भूतपूर्व उपनिवेशी अथवा अर्द्ध-उपनिवेशी देशों के सन्देश एवं राष्ट्रीय सम्मान को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखते हुए इनके प्रति पूरी मित्रता एवं सौहार्द दिखाना;
- (ii) इन देशों के पश्चिम के साथ अतीत के कटु सम्बन्धों का फायदा उठाते हुए इन्हें पश्चिम से और भी विमुक्त कर देना,
- (iii) न केवल उपनिवेशवाद-विरोधी बल्कि जानिवाद-विरोधी प्रवृत्तियों को भी उभारना;
- (iv) राजनीतिक तटस्थता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना,
- (v) औद्योगीकरण द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था को विकसित करने की महत्वाकांक्षा को महारा देना, हो सके तो मोडियन एवं पारम्परिक व्यापारों के सम्बन्ध को और भुजाना;
- (vi) पश्चिम के विरुद्ध उनके प्रत्येक भगड़े को उकसाना;

- (vii) विदेशी पूँजी या सहायता को उनकी स्वतन्त्रता एवं सम्मान के विरुद्ध बता कर सन्देह की भावना उभारना;
- (viii) उनके सम्मुख सोवियत रूस के तीव्र औद्योगीकरण को आदर्श के रूप प्रस्तुत करना ताकि स्थानीय लोग यह समझ सकें कि केवल साम्यवाद ही बहुत कम समय में ऐसी उपलब्धियों को साकार कर सकता है।

सोवियत संघ के शक्ति एवं प्रभाव के विस्तार के मुख्य आकराण केन्द्र हैं—अफ्रीका, एशिया एवं लेटिन अमेरिका।

ह्यूश्चेव ने सोवियत नीति को जो मोड़ दिया वह उनके पतन के बाद भी जारी रहा। बाद के सोवियत नेताओं की नीति ह्यूश्चेववादी ही रही और सोवियत प्रधानमंत्री कोसीगिन एवं राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव ने रूस की सह-अस्तित्व एवं शान्तिवादी नीति को आगे बढ़ाया।

ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल (अक्टूबर 1964-दिसम्बर 1980)

ह्यूश्चेव के पतन के बाद अक्टूबर, 1964 में सोवियत संघ का नेतृत्व ब्रेझ्नेव और कोसीगिन के हाथों में आया। नये नेतृत्व ने ह्यूश्चेववादी नीति अपनाते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में आस्था प्रकट की और साथ ही सोवियत कूटनीति को कुछ नई दिशाएँ भी प्रदान की।

सहअस्तित्व और यात्रा-कूटनीति—सहअस्तित्व और यात्रा-कूटनीति को आगे बढ़ाया गया। जून, 1967 में अमेरिका-रूस शिखर-सम्मेलन हुआ और पश्चिम एशिया के संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में रूसी प्रधानमंत्री कोसीगिन ने भाग लिया। सोवियत नेताओं ने भारत, पाकिस्तान, अमेरिका तथा अन्य देशों की यात्राएँ की। सोवियत विदेश नीति के विवाद-ग्रस्त पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या की गई जिससे समस्याओं के शान्तिपूर्ण निदान का मार्ग प्रशस्त हुआ।

ताशकन्द—सोवियत कूटनीति में नया मोड़—सितम्बर, 1965 में भारत-पाक संघर्ष का अन्त कराने में उल्लेखनीय प्रयास करने के उपरान्त दोनों देशों के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए मध्यस्थता करके रूस ने अपनी विदेश नीति के नए पैतरे से समूचे राजनीतिक विश्व को स्तब्ध कर दिया। सोवियत संघ ने इससे पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता के सिद्धान्त को कभी रबीकार नहीं किया था। जनवरी, 1966 में 'ताशकन्द वार्ता' को सफा बनाने में सोवियत कूटनीति अत्यन्त सक्रिय रही और फलस्वरूप 10 जनवरी 1966 को रात्रि के लगभग 9 बजे पाकि-राष्ट्रपति अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सोवियत प्रधानमंत्री कोसीगिन की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे 'ताशकन्द घोषणा' कहा गया। सोवियत राजनय की सफलता के मूल में प्रमुख कारण थे—(i) भारत और पाकिस्तान को एक निष्पक्ष वातावरण में समझौता बार्ता के लिए अग्रसर करना, (ii) समझौता कराने के प्रश्न को सोवियत

रूस द्वारा अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना, (iii) सोवियत रूस की भौगोलिक स्थिति और एशिया में शान्ति बनाए रखने में उसकी रुचि, एवं (iv) पाकिस्तान को चीन-अमेरिका के शिबिर में जाने से रोकने की प्रबल रूसी उत्कण्ठा।

पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण किन्तु शीघ्र ही भूल-बुधार—रूस के नए नेतृत्व का रूप ताशकन्द-समझौते के उपरान्त कुछ वर्षों तक भारत के प्रति उनका मैत्रीपूर्ण नहीं रहा जितना स्ट्रुश्चेव के समय था। कश्मीर के प्रश्न पर भी सोवियत रूस में पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नरमी आई। जुलाई, 1968 में रूस ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का जो निर्णय किया वह भारत की मित्रता और आशाओं पर एक करारी चोट थी फिर भी भारत का रख सहनशीलता और 'प्रतीक्षा करो और देखो' का रुढ़ा। उधर सोवियत नेता पाकिस्तान की दुरगो चालों से धुब्ध हो गए। उनकी यह धारणा बनी कि अमेरिका, चीन और रूस तीनों में से पाकिस्तान किसी का विश्वसनीय मित्र नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने ताशकन्द-समझौते के जो गम्भीर उल्लंघन किए उससे भी पाकिस्तान की ईमानदारी में सोवियत नेताओं का विश्वास टूट गया। दूसरी ओर भारत की गम्भीरता और दृढ़ता ने तथा रूस के प्रति अपरिवर्तित दृष्टिकोण ने सोवियत नेताओं को यह अनुभव करा दिया कि रूस के लिए अमेरिका और चीनी खतरे के विरुद्ध भारत जैसे शक्तिशाली व शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों के हाथों में कितनी सन्तुलनकारी शक्ति है।

भारत और रूस—1949 के अन्त तक भारत और इसके सम्बन्धों में सुधार होने लगा किन्तु जून, 1950 में कोरिया-युद्ध छिड़ने पर भटका लगा। भारत न्याय और निष्पक्षता के पक्ष में था, अतः उसने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने में कोई सकोच नहीं किया। इससे सोवियत संघ में भारत के प्रति रोष पैदा हो गया। लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेनाओं को 38वीं अक्षांश रेखा पार करने तथा चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के विरुद्ध चेतावनी दी तो स्टालिन को विश्वास हो गया कि भारत की निर्णय शक्ति स्वतन्त्र है, पश्चिम के दबाव से प्रेरित नहीं है। दोनों देश इसलिए भी एक-दूसरे के निकट आए कि सितम्बर, 1951 में भारत ने जापानी शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया क्योंकि यह सन्धि जापान को साम्राज्यवादी शिकजे में जकड़ने की एक चाल थी।

मोलेन्वोव और फिर बुल्गानिन-स्ट्रुश्चेव काल में भारत और रूस के सम्बन्ध अधिक पनिष्ट हुए। 1954 में रूस ने 'पंचशील' के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। जून, 1955 में नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की तथा रूसियों को अपनी सह-अस्तित्व की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित किया। 1955-56 में बुल्गानिन और स्ट्रुश्चेव ने भारत की यात्रा की। उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव में गम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण समान थे। कश्मीर-विवाद पर सोवियत संघ भारत को तुला समर्थन देता रहा और सुरक्षा-परिपद में भारत-विरोधी पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्तावों पर 'वीटो' का प्रयोग करता रहा। अक्टूबर, 1962 में चीनी आक्रमण के प्रारम्भ में रूसी रण-भारत के लिए

निराशाजनक रहा लेकिन दिसम्बर, 1962 में सुप्रीम सोवियत के सामने श्री एरुशेव ने भारत पर चीनी हमले की खुली निन्दा की। रूस द्वारा भारत को भिग विमान दिए गए और रूसी सहयोग से भिग विमान का कारखाना भी भारत में स्थापित किया गया।

26 फरवरी 1964 को एरुशेव के पतन के पश्चात् रूस में ब्रेझ्नेव और कोसीगिन के नए नेतृत्व का उदय हुआ। बाद के कुछ वर्षों में भारत को रूस का वैसा समर्थन नहीं मिल सका, जैसा एरुशेव ने दिया था। सितम्बर, 1965 में भारत-पाक संधि के समय सोवियत नेतृत्व की नीति किसी न किसी प्रकार संधि को शान्त करने की रही और रूस ने पाकिस्तान के कार्यों का पहले के समान विरोध नहीं किया। ताश्कन्द-समझौते के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में थोड़ा सा तनाव तब आया जब रूस ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का निषेध किया। रूस को अपने 'दिशा-भ्रम' का शीघ्र ही ग्रहसात हो गया और भारत-रूस सम्बन्धों में उत्तरोत्तर विकास होता रहा। बंगलादेश के सम्बन्ध में रूस का दृष्टिकोण भारत-समर्थक था। बंगलादेश के संकट के समय पीकिंग-पिण्डी-बांशिगटन धुरी के निर्माण की सम्भावनाओं और उससे उत्पन्न खतरे की दृष्टि से भारत ने 9 अगस्त, 1971 को सोवियत संघ के साथ मैत्री-शान्ति पर हस्ताक्षर किए। इस तरह भारत और सोवियत संघ चीन-अमेरिकी सम्बन्धों से भविष्य में उत्पन्न होने वाले परिणामों का मुकाबला करने के लिए और अधिक निकट आ गए। सुरक्षा-परिपद में भी रूस ने पाकिस्तान और उसके 'बड़े भाई' अमेरिका के मनसूबों पर पानी फेर दिया। युद्ध के दौरान उसने स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी ताकत हस्तक्षेप करने का दुस्ताहस न करे। इतना ही नहीं, जब अमेरिका का सातवां नैड़ा 'रहस्यमय इरादे' से बंगाल की खाड़ी की ओर चल गया तो रूस ने भी हिन्द महासागर में अपने मुद्रपोत इस दृष्टि से तैयार कर दिए कि भारत के विरुद्ध अमेरिका द्वारा नौ-सैनिक कार्यवाही करने पर उसका उचित उत्तर दिया जाए। नवम्बर, 1973 में ब्रेझ्नेव भारत आए। 30 दिसम्बर, 1973 को भारत और सोवियत संघ के बीच एक 15 वर्षीय आर्थिक और व्यापारिक समझौता हुआ। यह निश्चय प्रकट किया गया कि 1980 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को डेढ़ गुना या दुगुना बढ़ा दिया जाएगा। 1975 और 1976 के दौरान आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पारस्परिक सम्पर्क और सहयोग का विकास हुआ। कुछ समझौते भी किए गए। जून, 1976 में श्रीमती गांधी ने सोवियत संघ की यात्रा की। संयुक्त विज्ञप्ति पारस्परिक सहयोग और नीति-मार्तक्य की द्योतक थी।

मार्च, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। अप्रैल, 1977 में नए भारतीय नेतृत्व से विचार विनिमय के लिए सोवियत विदेशमन्त्री गोमिखो भारत आए। इस यात्रा के दौरान आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, व्यापार एवं दूरसंचार सम्बन्धों की स्थापना से सम्बन्धित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ग्रधिकीण अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में दोनों देशों के समान विचार पाए गए।

अक्तूबर, 1977 में प्रधानमंत्री श्रीर विदेशमन्त्री सोवियत संघ की राजकीय यात्रा पर गए। यह महत्वपूर्ण समझा गया कि आपसी मित्रता को न सिर्फ कायम रखा जाए बल्कि इसे और मजबूत किया जाए। इस बात पर भी सहमति हुई कि वर्ष 1978 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय व्यापार आदान-प्रदान के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर लाभपूर्ण आर्थिक सहयोग के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। संयुक्त विज्ञप्ति में भारत और सोवियत संघ ने शस्त्रों के लिए दौड़ को समाप्त करने, आणविक युद्ध को टालने और निःशस्त्रीकरण सम्मेलन कराने के काम को महत्वपूर्ण बताया। दोनों पक्षों ने यह माना कि एशियायी देशों के बीच आपसी लाभ के सहयोग को अवश्य बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए। हिन्दमहासागर में शान्ति क्षेत्र बनाए रखने की इच्छा का समर्थन किया। दोनों पक्षों ने हिन्दमहासागर से सभी वर्तमान सैनिक श्रद्धों को हटाने और नए श्रद्धे बनने पर रोक लगाने की माँग की।

पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों के प्रति सोवियत-नीति—रूस पूर्वी यूरोप के साम्यवादी जगत पर अपना प्रभाव बनाए रखने की नीति पर चलता रहा ताकि वहाँ में पश्चिमी यूरोपीय राजनीति में प्रभावपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः पूर्वी यूरोप के देशों में पनप रही सोवियत-विरोधी प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए उसने वारसा पैकट को पहले की अपेक्षा और अधिक कठोर तथा मुद्द बनाने दिया। 1967 से ही चेकोस्लोवाकिया में उदारवादी प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। जनवरी, 1968 में हुबचेक के नेतृत्व में चेकोस्लोवाकियाई साम्यवादी दल ने समाजवादी लोकतन्त्रीकरण का सिद्धान्त स्वीकार करके उदारवाद के पक्ष में बहुत से मुद्दा प्रस्तावित किए। जब चेकोस्लोवाकिया के नेताओं ने रूसी नाराजगी की कोई परवाह नहीं की तो 21 अगस्त, 1968 की रात्रि को सोवियत रूस तथा वारसा पैकट के चार अन्य देशों—पोलैण्ड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी और बल्गेरिया की शक्तिशाली सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके कुछ ही घण्टों में राजधानी प्राग सहित अन्य बड़े नगरों पर अधिकार कर लिया। आखिर काफी विचार-विमर्श के बाद मास्को में दोनों पक्षों के बीच एक सम्मेलन हुआ जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चेकोस्लोवाकिया सरकार ने वचन दिया कि वह चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद को मुद्द बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। सितम्बर, 1968 के मध्य तक प्राग से सोवियत सेनाएँ वापस सौट गईं। अप्रैल, 1969 में हुबचेक के नेतृत्व का अन्त हो गया और सोवियत-समर्थक सरकार का निर्माण हुआ।

कम्युनिस्ट देश भी अपने पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करने को प्रेरित हुए। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टोटो एक लम्बे अन्तराल के बाद अगस्त, 1977 में राजकीय यात्रा पर सोवियत संघ गए और वहाँ उत्तर बाल्किया होने हुए 30 अगस्त को पहली बार चीन पहुँचे। सोवियत संघ टोटो से गबाद स्थापित करने की पहल कर चुका था। ब्रेज्नेव ने सितम्बर, 1977 को अपनी बेलग्रेड यात्रा

के अवसर पर आश्वासन को दोहराया कि सोवियत संघ यूगोस्लाविया की स्वाधीनता का आदर करता रहेगा और याथा के बाद जारी की गई विज्ञप्ति में दोनों देशों के बीच 'स्वैच्छिक सहयोग' की बात प्रकट की गई। सोवियत संघ ने एक तरह से समाजवाद का अपना मार्ग अपने-आप तय करने के यूगोस्लाविया के प्राग्रह को भी मान्यता दे दी।

मार्शल टीटो विश्व के साम्यवादी आन्दोलन को विघटन से बचाने के लिए चीनी और रूसी नेताओं से गम्भीर विचार-विमर्श के पक्ष में थे। उन्हें यह नागवार था कि दुनिया का साम्यवादी आन्दोलन तीन भागों में बँट जाए—सोवियत साम्यवाद, मार्सोवादी, तथा यूरोपीय साम्यवाद।

लेटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के सम्बन्ध में सोवियत नीति—सोवियत संघ ने अपना ध्यान यूरोप और एशिया की ओर केन्द्रित कर रखा है। लेटिन अमेरिका और अफ्रीका के सम्बन्ध में उनकी विदेश नीति विशेष सक्रिय नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं—प्रथम, लेटिन अमेरिका और अफ्रीका भौगोलिक दृष्टि से सोवियत संघ से बहुत दूर हैं। द्वितीय, इन क्षेत्रों में स्थित कांगों, क्यूबा, घाना, मुहान आदि देशों में उसे यह कटु अनुभव हो गया है कि साम्यवाद का स्वागत करने के लिए लेटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं।

रूस एवं अमेरिका तथा पश्चिमी गुट—ब्रेज्नेव-कोभीगिन-युग के रूस ने अमेरिका और पश्चिमी गुट के साथ अवसरानुकूल शीतयुद्ध को उभार देकर भी स्टालिन के ममान स्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं किया। उत्तरी कोरिया में जाँतसत और निकमन प्रशासन के मध्य हुए अमेरिकी जासूनी काण्डों के समय भी सोवियत रूस ने सतम ही प्रदर्शित किया। विपन्नताम-ममस्या पर भी रूस का यही रुख रहा कि वार्ता द्वारा समस्या का समाधान हो जाए। उत्तर विपन्नताम को विज्ञान मंत्रिक सहायता देने हुए भी रूसी नेताओं ने ऐसा कोई बातावरण पैदा नहीं किया जिसमें अमेरिका के साथ समझौता-वार्ता के द्वार बन्द हो जाएँ। विपन्नताम में युद्ध-विराम में भी सोवियत लूटनीति का महत्वपूर्ण हाथ रहा। दोनों देशों के नेताओं द्वारा सहयोगपूर्ण रुख अपनाते के फलस्वरूप ही नवम्बर, 1971 में बर्लिन सम्झौता सम्पन्न हो सका था। मई, 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन की मास्को-यात्रा अपने-आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। किन्तु भी अमेरिकी राष्ट्रपति की सोवियत संघ की यह पहली यात्रा थी और इस प्रथम यात्रा के दौरान ही दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण सन्धियों पर हस्ताक्षर हुए। सबसे महत्वपूर्ण 'भीषण शस्त्रास्त्र परिधीमन सन्धि' (Strategic Arms Limitation Treaty—SALT) थी जिसमें दोनों महाशक्तियों ने एक-दूसरे की शक्ति के मामले भुक्त हो भय मिथित आत्म-विश्वास का एक नया सन्तुलन कायम किया। अक्टूबर, 1972 में सोवियत संघ ने भारी मात्रा में गेहूँ खरीदने के लिए अमेरिका से एक दीर्घकालीन समझौता किया और 18 नवम्बर, 1972 को दोनों देशों के बीच हुई एक व्यापारिक सन्धि में रूस ने सहमति प्रकट की कि द्वितीय महायुद्ध के समय उसने अमेरिका में जो उधार

पट्टा ऋण लिया था उस राशि को वह चुका देगा। एक अन्य सन्धि में यह तय हुआ कि अगले तीन वर्षों में दोनों देशों के आपसी व्यापार में तीन गुना वृद्धि कर दी जाएगी। ये दोनों व्यापारिक सन्धियाँ इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण थीं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध नगण्य थे।

जून, 1973 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ब्रेझ्नेव ने अमेरिका की नौ दिवसीय यात्रा की। इस अवसर पर भी दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। मिद्धान्त यह स्वीकार कर लिया गया कि 1974 तक दोनों महाशक्तियों परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर स्थायी रोक लगा देगी और परमाणु-शक्ति के ज्ञानि-पूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोगपूर्वक काम करेंगी—एक सन्धि जिसका उद्देश्य परमाणु युद्ध को रोकना था। सन्धि के अन्तर्गत दोनों पक्षों की ओर से यह संकल्प लिया गया कि उनमें से कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करेगा, परस्पर एक-दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तीसरी धमकी देगा और न ही बल का प्रयोग करेगा। अगस्त, 1973 में दोनों के बीच पुनः एक समझौता हुआ जिसके अनुसार 1975 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ानों का कार्यक्रम बालू करने का निश्चय किया गया। जून, 1974 में राष्ट्रपति निकसन ने पुनः सोवियत संघ की यात्रा की और इस अवसर पर भी दोनों देशों के बीच कुछ समझौते सम्पन्न हुए। नवम्बर, 1974 के ब्याडीबोस्टोक में फोर्ड-ब्रेझ्नेव शिखर-वार्ता हुई। जुलाई, 1975 में अगोलो सोयुज संयुक्त अन्तरिक्ष कार्यक्रम में दोनों ने सहयोग किया। 1980 के मध्य तक दोनों देशों के सम्बन्ध, बावजूद सामयिक उत्तेजनाओं के समय और सुधार का दिशा-भक्तेत देते रहे, तथापि सम्बन्धों में उतनी सौहार्दता नहीं दिखाई दी, जितनी निकसन और फोर्ड-प्रशासन के दौरान रही थी। क्यूबा में सोवियत सलाहकारों की उपस्थिति, अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के प्रवेश आदि की घटनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ी और मतभेद तीव्र हुए, लेकिन दोनों ही पक्षों ने समय और सहनशीलता की राजनीति अपनाकर विश्व-शान्ति बनाए रखने में योग दिया। 8 जनवरी 1980 को अमेरिका द्वारा 17 कमियों के निष्कासन को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव अधिक बढ़ गया और उसी दिन सुरक्षा परिषद् द्वारा अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस ने अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग किया, तथापि 15 जनवरी, 1980 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर दिया। अफगानिस्तान में, वहाँ की सरकार के आग्रह पर सोवियत सैनिक शक्ति बढ़ी मात्रा में टिढ़ी रही तथापि इस मुद्दे पर एम-अमेरिका के बीच तनाव उतना तीव्र नहीं रहा जितना पहले था। ईराक-ईरान युद्ध में दोनों देशों ने अहस्तशेष की नीति अपनायी। अक्टूबर, 1980 में काट्टर ने यह विश्वास व्यक्त किया कि सोवियत मध्य-प्राचीन क्षेत्र में युद्ध को रोकना नहीं चाहता, तथापि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सोवियत मध्य के ईरान प्रथम छाडी की नियन्त्रित कर सजने वाले रिमी भी क्षेत्र में दखल करने से अमेरिकी सुरक्षा को सर्वाधिक घतरा उत्पन्न होना।

यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के साथ भी सोवियत रूस ने सम्पर्क और सहयोग-सूत्र विकसित करने के प्रयत्न जारी रखे। जून, 1973 में ब्रेझ्नेव फ्रांस में राष्ट्रपति पोम्पिडू से मिले। अक्टूबर, 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति बालेरी जिसकार द एस्टें ने सोवियत संघ की राजकीय यात्रा की। इन यात्राओं से दोनों देशों के दृष्टिकोण में अधिक निकटता आई। जून, 1977 में सोवियत साम्यवादी पार्टी के महासचिव ब्रेझ्नेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद भी सम्भाल लिया। राष्ट्रपति बनने के बाद ब्रेझ्नेव की सबसे पहली यात्रा पेरिस की थी। अमेरिका और रूस के सम्बन्धों में जो दुराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी उसको देखते हुए ब्रेझ्नेव ने एक बार, फिर फ्रांस के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। फ्रांस का यह रुझ भी स्पष्ट था कि वह रूस को यूरोप में एक महत्वपूर्ण मित्र और भागीदार मानना है। फ्रांस के अलावा पश्चिम जर्मनी के साथ भी रूस के सम्बन्ध सुधरे।

रूस तथा कुछ अन्य देश एवं क्षेत्र—बंगला देश के प्रति रूस की प्रारम्भ से ही सहानुभूति रही। बंगला देश के मुक्ति संघर्ष में रूस ने अपना नैतिक और राजनीतिक समर्थन दिया और रूस ने बंगला देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में रुचि लेकर पारस्परिक आदान-निर्दान सम्बन्धी समझौता भी सम्पन्न किया। विश्व-संस्था में बंगला देश के प्रश्न पर जो संघर्ष हुआ उसमें रूस ने बंगला देश को पूर्ण समर्थन दिया। जापान के साथ भी सम्बन्ध-सुधार के लिए रूस प्रयत्नशील रहा। जापान में भी इस धारणा को बल मिला कि सोवियत संघ के साथ आर्थिक सहयोग जापान के हित में है। भूमध्य सागर में रूस की रुचि अधिकाधिक बढ़ती गई। रूस की आकांक्षा रहो कि वह भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था पूर्वी यूरोप के देशों जैसी ही बना दे ताकि इन देशों के साथ मास्को के सम्बन्ध पूर्वी यूरोप के देशों जैसे हो जाएँ। भूमध्य सागर में अधिकाधिक प्रवेश से सोवियत संघ ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी वृद्धि कर ली।

एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए सोवियत कूटनीति ने 'ब्रेझ्नेववाद' को अपनाया। यह विचार 1969 में सोवियत नेता ब्रेझ्नेव ने रखा था जिसमें अस्पष्ट रूप से एशियायी देशों के लिए एक सुरक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। 1972 से इस योजना को पुनः रखा गया और अफगान प्रधान मन्त्री के स्वागत पर बोलते हुए कोसीगिन ने कहा—“एशिया की सुरक्षा का सही रास्ता सैनिक गुट नहीं है और न ही कुछ राष्ट्रों द्वारा हमारे राष्ट्रों का विरोध करना है, बल्कि यह रास्ता देशों के बीच अच्छे पड़ोसी का आतावरण पैदा करना है।” पर साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि शान्ति स्थापित करने का सोवियत संघ का रास्ता सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि सोवियत विदेश-नीति की सबसे महत्वपूर्ण दिशा राष्ट्रों की आजादी और स्वायत्तता का अतिरक्षण करने वाला साम्राज्यवादियों को पराजित करने के लिए युद्ध और संघर्ष-स्थलों को समाप्त करना है। इस धारणा से यह आभास हुआ कि रूसी नेताओं का सुरक्षा-निश्चान्त का नया 'पवशील' होने के

वायजुद सैनिक हस्तक्षेप या सैनिक हल से रहित नहीं है। एशियायी राजनीतिक क्षेत्रों में यह आशंका बनी रही कि यद्यपि ब्रेझ्नेव-सिद्धान्त में एशियायी सुरक्षा व्यवस्था निहित है और साथ ही इसके लक्ष्य अमेरिका और चीन भी हैं तथा रूस हिन्द महासागर में अपने प्रभाव का आकांक्षी है। भारत ने भी इस योजना के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। वास्तव में रूस का एशिया सुरक्षा सिद्धान्त अभी कोई साकार रूप नहीं ले सका है।

वियतनाम युद्ध में साम्यवादी शक्तियाँ उत्तरी वियतनाम की पीठ पर थी। सोवियत रूस ने वियतनाम को भरपूर सैन्य सामग्री पहुँचाई। अनुमानतः उत्तर वियतनाम को दी जाने वाली सैन्य-सहायता में रूस का भाग 80 प्रतिशत और चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों का लगभग 20 प्रतिशत था। सोवियत नीति वियतनाम संघर्ष के शान्तिपूर्ण समाधान की थी। रूस-अमेरिका के समझौतावादी हल और वियतनाम के सम्बन्धित पक्षों के विवेक के फलस्वरूप ही वियतनाम-युद्ध का अन्त हो गया।

पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए रूस और अमेरिका दोनों ही प्रयत्नशील रहे। रूसी नीति अरब राष्ट्रों को कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक सहयोग देने की रही जबकि अमेरिका ने इजराइल को हर प्रकार की मदद दी। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में सोवियत सघ के प्रभाव में धीरे-धीरे परिवर्तन आया। छत्रुश्चेव काल में सोवियत सघ को 'अरब हितों का संरक्षक' समझा जाता था, किन्तु 1967 के अरब-इजराइल युद्ध में अरब राष्ट्रों के पराजय के कारण सोवियत कूटनीति को काफी आघात लगा। इस युद्ध में अरब राष्ट्रों ने सोवियत सघ पर दबाव डाला था कि वह युद्ध में हस्तक्षेप करे, परन्तु वह युद्ध में नहीं जुड़ा था। अरबों का पुनः विश्वास प्राप्त करने के लिए मई, 1971 में सोवियत सघ ने मित्र के साथ एक 15 वर्षीय पारस्परिक सुरक्षा समझौता किया, किन्तु अगले वर्ष ही सोवियत सघ और मित्र के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो गया और राष्ट्रपति सादात ने रूस के सैनिक विशेषज्ञों को मित्र छोड़ने का आदेश दिया। विगाड़ का यह दौर अंधेरा नहीं चला और जब अक्टूबर, 1973 में चौथा अरब-इजराइल युद्ध हुआ तो अरबों ने रूसी शस्त्रास्त्रों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रगति पुनः प्राप्त कर ली। आगे चलकर तनाव पुनः पैदा हो गया। अरब-इजरायल समस्या के समाधान में अमेरिका रूस से बाजी मार ले गया और सितम्बर, 1975 में वह दोनों पक्षों के बीच एक अन्तरिम समझौता कराने में सफल हुआ। मार्च, 1976 में सादात ने रूस के साथ 15 वर्षीय मैत्री सन्धि को भंग कर दिया। मित्र के साथ तनाव के बावजूद लीबिया, सीरिया, जोर्डन, कुवैत आदि अन्य राष्ट्रों के साथ रूस की निरन्तरता में वृद्धि हुई और ये राष्ट्र रूस से भारी मात्रा में सैनिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने लगे। सितम्बर, 1978 में अमेरिका में गेप डेविड में कार्टर की उपस्थिति में जो बेनिन-नादात समझौता हुआ उससे पट्ट पुनः स्पष्ट हो गया कि अमेरिका पश्चिम-एशिया में रूसी प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ा है। आज

पश्चिमेशिया में रूस की तुलना में अमेरिका का प्रभाव अधिक है। मिस्र-अमेरिका सम्बन्धों में सुधार के साथ-साथ मिस्र-रूस सम्बन्ध शिथिल हो गए हैं।

सोवियत-संघ और टर्की में भी मधुर सम्बन्धों की शुरुआत हुई। दिसम्बर, 1975 में सोवियत प्रधान मंत्री कोसीगिन लगभग 10 वर्ष के अन्तराल के बाद पुनः टर्की गए। सोवियत प्रधानमंत्री ने टर्की के भूभण्डसागरीय बन्दरगाह तियन्दरिया में सोवियत सहायता से निर्मित इस्पात सुयन्त्र का उद्घाटन किया। रूस के साथ मैत्री के शुभारम्भ के बावजूद टर्की और अमेरिका के बीच मैत्री सम्बन्ध पीके नहीं पड़े और मार्च, 1976 में दोनों देशों के बीच एक चार-वर्षीय सैनिक समझौता हुआ। टर्की के प्रधान मंत्री ने 1978 के मध्य मास्को-प्यात्रा की जिम्मे दोनो देशों के बीच सम्बन्धों में और भी निश्चिन्ता आई है।

कोसीगिन के बाद नवम्बर 1980 से मार्च 1982 तक सोवियत विदेश-नीति

अक्तूबर, 1980 में सोवियत संघ के 76 वर्षीय प्रधान मंत्री थी ग्लैस्मेयी कोसीगिन के अवकाश ग्रहण करने के बाद थी निकोलाई तिखोन्व सर्वोच्च सोवियत के 1500 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से नये प्रधान मंत्री चुने गये। इस प्रकार अब ब्रेझ्नेव तिखोन्व काल शुरु हुआ। नये नेतृत्व के अन्तर्गत मार्च 1982 तक सोवियत विदेश-नीति में कोई नया दिशा-परिवर्तन नहीं हुआ और विश्व के विभिन्न देशों, क्षेत्रों तथा समस्याओं के प्रति सोवियत रूस लगभग वही रूढ़ जो ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल में रहा था। नवम्बर 1980 से मार्च 1982 तक सोवियत विदेश-नीति की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार रही—

(i) ब्रिटिश सूत्रों के अनुसार सोवियत संघ ने सीरिया को इजरायल के परमाणु प्राप्ति के किसी भी स्तर से बचाने का आग्रह किया।

(ii) 23 फरवरी, 1981 को केंब्रिज में सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी की 26वां कांग्रेस में सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव ने नये अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से शिल्लर वार्ता का प्रस्ताव किया। उन्होंने अपने भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर अधिक बल देते हुए एक आठ सूची योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है—

1. तेना, तीसेना और वायुसेना के अग्रसार और संचालन को नियमित करने के बारे में कहा गया है कि सोवियत संघ यूरोपीय भाग से अपने सैनिक हटा सकता है वहाँ पश्चिमी राष्ट्र भी इस तरह के विश्वास का आग्रह कर सकते हैं।

2. सुदूर पूर्व के देशों के बारे में सभी सम्बन्धित देशों के साथ सोवियत संघ ठोस वार्ता के लिए तैयार है।

3. अफगानिस्तान के प्रश्न पर हमें वार्ता से इनकार नहीं, वहाँ फ़ारम की खाड़ी के सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श हो। इस क्षेत्र में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए।

4. जहाँ तक सामरिक अस्त्र परीक्षण सम्बन्ध (सांख्यिक) का प्रश्न है। हम अविलम्ब अमेरिकी प्रशासन से वार्ता के लिए तैयार हैं। जिन क्षेत्रों में निश्चित परिणाम प्राप्त किए जा चुके हैं सोवियत संघ उसे वार्ता पटल पर रखना चाहेगा।

सैन्य-नामयी और विमान देकर इस उप-महाद्वीप में शक्ति-मन्तुलन को बिगड़ने नहीं देगा।

सोवियत विदेश-नीति का मूल्यांकन

मुद्रोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की जटिलताओं में सोवियत विदेश-नीति अभी तक जितनी सकल और प्रभावकारी रही है, उतनी अमेरिकी विदेश-नीति नहीं। पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप आदि सभी क्षेत्रों में सोवियत रुम ने अपना प्रभाव बढ़ाया है और अमेरिका तथा उसके साथी राष्ट्रों की चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। महायुद्ध के बाद तीन वर्गों में ही सोवियत रुम ने पूर्वी यूरोप को बाल बना देने में सफलता प्राप्त की। पश्चिमी एशिया में अरब जगत् पर सोवियत रुम आपत्तचर्चजनक ढंग से छा गया और भारत तो उसका प्रगाढ़ मित्र है। भारत के साथ रुमी मैत्री की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रुम ने भारत की गुट-निरपेक्षता को पूरा सम्मान देने हुए उसकी मित्रता स्वीकार की है। भूमध्यसागर और हिन्द महासागर में सोवियत नीति का प्रभावी वर्चस्व है। जापान के साथ भी रुस के सम्बन्ध मधुर बनने जा रहे हैं और दोनों पक्षों में आर्थिक सहयोग की नींव पर राजनीतिक सम्बन्धों का महल खड़ा किया जाते लगा है। पश्चिमी जर्मनी से समझौता करके भी रुस ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की है। फ्रान्स तब कुछ वर्षों से रुम के पक्ष में जितना झुका है वह स्थिति अमेरिकी गुट की अपेक्षा रुम के लिए अधिक उत्साहवर्धक है। अमेरिका के अतिरिक्त केवल चीन ही रुमी विदेश-नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अमेरिका और रुम में पक्ष के पीछे परस्पर सहयोग और सहस्रसित्व की जो गुप्त बान्धन चल रही हैं उनमें अतिरिक्त यही अनुमान है कि निकट भविष्य में चीन रुम के साथ प्रतिद्वन्द्विता त्याग कर पुनः सहयोग की नीति का अनुसरण करने लगेगा। भारत जिस शक्तिशाली रूप में उभरा है उससे भी चीन की मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

सोवियत मध्य के शान्तिपूर्ण सहस्रसित्व के तारे पर अनेक राजनीतिक क्षेत्रों में सन्देह प्रकट किया जाता है, लेकिन यदि हम अमेरिका के रवंगे को देखें तो जायद रुम से भी अधिक सन्देह उस पर किया जाना चाहिए। बगला देण के लोकतान्त्रिक जन-आन्दोलन को कुचलने में अमेरिका ने जो लज्जाजनक भूमिका अदा की, वह अमेरिकी लोकतन्त्र के नाम पर बलक है। भारत के न्यायोचित पक्ष का गला घोटने और युद्ध-पिपासु पाकिस्तानी तानाशाहों को हथियारों में लैम करने में भी अमेरिका की भूमिका निन्दनीय रही है। फिर आज का युग आणविक अस्रों का युग है जिसमें युद्ध की दशा में परमाणु अस्त्र न बिखेरा की लाज रगेंगे न विजित की, अतः सह-सन्तान का विफल सह-विनाश ही रह गया है और जायद कोई भी महाशक्ति इस मार्ग को अपनाता पसन्द नहीं करेगी। यही कारण है कि चीनी अजगर जो युद्ध की फूँकारें मारता था, अब युद्ध और शान्ति की मिथित फूँकारें छोड़ने लगा है।

संयुक्तराज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय और उसकी विदेश नीति

(Rise of U. S. A. as Super Power and Its Foreign Policy)

“इस दस्तावेज में जो बुनियादी सिद्धान्त निरूपित किए गए हैं वे उन उत्तरदायित्वों के लिए बाधक साबित नहीं होंगे जो अमेरिका और सोवियत संघ अन्य देशों के बारे में पहले स्वीकार कर चुके हैं।”

—संयुक्त घोषणा, मास्को-सितर धार्ता, 1972

द्वितीय महायुद्ध इतना व्यापक और प्रभावकारी था कि इसके अन्त के साथ ही विश्व-इतिहास के एक युग का अन्त हो गया। एक नूतन युग का सूत्रपात हुआ जिसमें अनेक राज्य उभरे, नई महाशक्तियों का उदय हुआ, प्रभुत्व-क्षेत्र बदले, नई प्रवृत्तियों और नए सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में नई समस्याएँ उत्पन्न हुईं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक यूरोप विश्व-इतिहास का निर्माता था। 1942 में कोलम्बस द्वारा नई दुनिया अर्थात् अमेरिका की खोज से लेकर 1939 तक के युग को विश्व-इतिहास का यूरोपीय युग कहा जाता है। लेकिन महायुद्ध ने इस ‘यूरोपीय’ युग का अन्त कर दिया। महायुद्ध ने यूरोप को आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक सभी दृष्टियों से पंगु बना दिया। महायुद्ध के बाद का यूरोप एक ‘समस्या-प्रधान यूरोप’ (A Problem Europe) बन गया। जर्मनी और इटली नष्ट हो गए तथा ब्रिटेन और फ्रांस तृतीय श्रेणी के राष्ट्र बन गए। विश्व-नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकल कर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के हाथों में आ गया। महायुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भव संसार में दो ही महाशक्तियाँ रह गई हैं—संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अब ये दोनों ही देश प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप में उदित हुए और गुडोत्तर विश्व तेजी से इनके प्रभाव-क्षेत्रों में बँटने लगा। दोनों राष्ट्र मानव-चिन्तन की दो प्रबल विचारधाराओं के प्रतीक बन गए। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधि बना तो संयुक्त राज्य अमेरिका

सोवियतवादी आकांक्षाओं का पक्षधर बन गया। दो शिविर प्रकट हुए—संयुक्तराज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवादी शिविर और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी शिविर।

संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय (Rise of U. S. A. as Super Power)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेते हुए ही हमें देखना होगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय 'एक महाशक्ति' के रूप में किस प्रकार हुआ। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका महायुद्ध के पूर्व से ही एक समृद्ध और शक्तिसम्पन्न देश था, लेकिन उसे 'महाशक्ति' का वह स्तर प्राप्त नहीं था जो युद्धोत्तरकाल में प्राप्त हुआ। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक वह यथासम्भव पृथक्तावादी नीति का अनुसरण करता रहा। राष्ट्रपति जैफरसन ने 1801 की इस नीति को इन शब्दों में स्पष्ट किया था—“शान्तिपूर्ण व्यापार सबके साथ झगड़ पंदा करने वाली सन्धियाँ किसी के साथ नहीं।” इसका आशय यही था कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करेगा लेकिन यूरोपीय राजनीति के जाल में नहीं फँसेगा। 1823 में अमेरिका की विदेशनीति में सुप्रसिद्ध 'मुनरो सिद्धान्त' (Monroe Doctrine) का प्रवेश हुआ। राष्ट्रपति मुनरो ने एक ओर तो यह कहा कि अमेरिका यूरोपीय विवादों से पृथक् रहेगा, लेकिन दूसरी ओर यूरोपीय राज्यों को यह चेतावनी भी दी कि वे अमेरिका महाद्वीप में साम्राज्यवादी चेष्टाओं से दूर रहें। यदि अमेरिकी गोलार्द्ध में हस्तक्षेप किया गया तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका अनैवीपूर्ण कार्यवाही समझेगा। दूसरे शब्दों में, मुनरो सिद्धान्त का अर्थ था—“तुम पृथक् रहो, हम भी पृथक् रहेगे।” प्रथम महायुद्ध तक मुनरो सिद्धान्त और पृथक्तावादी नीति का मेल भली-भाँति चलता रहा, लेकिन महायुद्ध आरम्भ हो जाने पर अमेरिका के लिए परम्परागत नीति पर चलते रहना सम्भव नहीं रहा। आरम्भ में तटस्थ रहने के बाद अमेरिका भी मित्रराष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में तूट पड़ा। 6 अप्रैल, 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार 1793 से चली आ रही पृथक्तावादी एवं तटस्थतावादी अमेरिकी नीति का पहली बार सम्पूर्ण रूप में परित्याग हुआ। अमेरिकी सैन्य-शक्ति ने युद्ध का पासा पलट कर जर्मनी को भीषण पराजय की निश्चित बना दिया। विजयी जर्मनी पराजित जर्मनी में बदल गया और 11 नवम्बर, 1918 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करते हुए विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिए।

दो महायुद्धों के बीच अमेरिका

प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति विल्सन ने अपने देश को अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग पर चलाना चाहा, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। सीनेट के विरोध के कारण अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य तक नहीं बन सका। इस प्रकार अमेरिका में पृथक्तावादी नीति का पुनरोदय हुआ।

विल्सन ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा : “हमें विश्व नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था, किन्तु हमने इसे खो दिया तथा शीघ्र ही हमें इन सबका दुष्परिणाम जान हो जाएगा।”

यद्यपि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका ने पृथक्तावादी नीति को अपनाया तथापि इसके कारण उसका प्रभाव विश्व राजनीति में कम नहीं हुआ। अवश्य ही यदि उसने सत्रिय रूप से भाग लिया होता तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता। वास्तव में अमेरिका की शक्ति अनेक तत्त्वों पर आधारित थी, जैसे प्राकृतिक साधन, औद्योगिक तकनीकी तरीके, उद्यमी एवं साहसी जनता की गत्यात्मक प्रकृति, आदि। केवल यही सब कुछ नहीं था। युद्ध के समय माँग के कारण उत्पादन एवं आविष्कार की गति पर्याप्त तेज हो गई थी। विश्वव्यापी व्यापार की व्यवस्था के कारण अमेरिकी-वाणिज्य को नए विदेशी बाजार स्थापित करने के अवसर एवं क्षमता प्राप्त हुई। विश्व की वित्तीय राजधानी लन्दन की अपेक्षा वाशिंगटन बन गई। 1930 तक अमेरिका के व्यापार और वित्त की स्थिति पर्याप्त एकीकृत हो गई।

वस्तुतः अमेरिका दुनिया के आर्थिक और वित्तीय मामलों में एक प्रभावशाली योगदान कर रहा था। वह यूरोप के पुनर्निर्माण में कर्ज और भेंट प्रदान कर रहा था। व्यक्तिगत एवं सरकारी अभिकरणों की राहत के लिए एवं पुनर्रचना के लिए प्रचुर धन खर्च किया जा रहा था। अमेरिका द्वारा जर्मनी, फ्रांस और इटली को उनकी साख बनाए रखने के लिए पर्याप्त मदद दी गई। इसके साथ ही स्थानीय संग्रार की इकाइयों, सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं व्यक्तिगत नियमों को कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इस देश ने पोलैण्ड में रेल निर्माण के लिए यूगोस्लाविया में बन्दरगाह निर्माण के लिए तथा भास्त्रिया में गृह निर्माण के लिए सहायता की। मध्यपूर्व में तेल के नए कुएँ खोदने के लिए, क्यूबा में चीनी के नए उद्यम स्थापित करने के लिए, टोकियो तथा शंघाई में सार्वजनिक उपयोगिताओं के विकास के लिए पर्याप्त डॉलर खर्च किया गया। संयुक्तराज्य अमेरिका को सोवियत रूस से भी पर्याप्त आर्थिक लेन-देन रहा। वैसे अमेरिका ने 1933 तक सोवियत रूस को नृटनीति का मान्यता प्रदान नहीं की थी, तथापि व्यापार के नए बाजार खुलना नहीं रुक सका।

वास्तव में शुरू से ही अनेक कारणोंवश अमेरिका की शक्ति और महत्ता बढ़ती चली गयी :

1. अमेरिका के अपने उपनिवेश थे, अपना एक साम्राज्य था। इसने विश्व में उसका स्थान महत्त्वपूर्ण बन गया। अमेरिका का दक्षिण की दिशा में लैटिन अमेरिकन राज्यों पर और पश्चिम की ओर एशियायी तटों पर पर्याप्त प्रभाव था। इस महाद्वीप में उसकी स्थिति सर्वोच्च थी और भी अधिक महत्त्वपूर्ण ब्रिजन द्वीप-समूह डेनमार्क से स्वरीड लिए गए थे। पनामा नहरी क्षेत्र पर 908 में अमेरिका का नियन्त्रण था। क्यूबा में उसका एक महत्त्वपूर्ण सैनिक प्रभु था। पनामा

गणराज्य, निकारगुआ, हेट्टी तथा डोमिनिकन गणराज्य बहुत कुछ सुरक्षक राज्य की स्थिति में थे। प्रशान्त क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी रक्षा के लिए एल्यूसियन महाद्वीपों से हवाई होते हुए पनामा नहर क्षेत्र तक एक पंक्ति की स्थापना की। बाद में विलियम मिचेल ने 1935 में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि वायु शक्ति एलास्का की धरती को सबसे अधिक सामरिक महत्व का स्थान बना देगी और जो कोई भी एलास्का पर अधिकार रखेगा वह सारी दुनिया पर शासन करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशान्त क्षेत्र के उपनिवेशों में हवाई का सम्बन्ध घनिष्ठ था। जब से इसे स्पेन-अमेरिकी युद्ध में लिया था तब से इसको सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। अमेरिका से दूर स्थित सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं कष्टदायक समुद्रपारीय प्रदेशों में फिलिपाइन द्वीप-समूह था। यह भाषा की गयी कि इनके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशान्त महासागर में नौसैनिक एवं व्यापारिक सर्वोच्चता प्राप्त हो जाएगी, किन्तु बाद में यह भावना और जोर पकड़ने लगी कि आक्रमण की दशा में उनकी रक्षा नहीं की जा सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कालान्तर में प्रकट किया कि फिलिपाइन के लोगों को पर्याप्तत्व प्राप्त सरकार प्रदान कर अमेरिका अन्त में उनको पूर्ण स्वतन्त्रता दे देगा। फिलिपाइन के सम्बन्ध में अमेरिकी नीति विरोधाभासपूर्ण थी क्योंकि एक ओर तो उसने यहाँ के लोगों को स्थायित्व सरकार प्रदान कर स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित किया, दूसरी ओर इसके प्रति जो आर्थिक नीति अपनायी उसके परिणामस्वरूप यह प्रदेश अधिकाधिक आश्रित होता गया। वैसे अमेरिका इस प्रदेश पर नियन्त्रण रखने में रुचि नहीं ले रहा था, किन्तु यह नियन्त्रण को हटाना भी नहीं चाहता था। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ से पुगना राजनीतिक साम्राज्यवाद तो हट रहा था, किन्तु नए प्रकार का आर्थिक साम्राज्यवाद छा रहा था।

2. नौसेना का विकास—जब अमेरिका ने आर्थिक शक्ति को अपने प्रभाव का मौलिक आधार बना लिया तो यह जरूरी था कि उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए अमेरिकी नौसेना का विकास किया जाता। थियोडोर रूजवेल्ट ने 1900 में ही जो नौसेना शक्ति का विकास किया, उसके कारण ही अमेरिका हवाई और क्यूबा आदि में नौसैनिक घड़ड़े खोल सका तथा कैरिबियन और पूर्वी प्रशान्त महासागर पर अपनी अधिकार रख सका। प्रथम विश्वयुद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका को तेजी से अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर प्रेरित किया। दो महायुद्धों के बीच अमेरिका एक प्रबल नौ-शक्ति बन गया।

3. अमेरिकी निर्यात—अमेरिकी शक्ति को बढ़ावा देने वाले तत्वों में इसके द्वारा दिए जाने वाला सामान, डॉलर, सेबीवर्ग और विचारों का निर्यात था। यूरोप में तथा एशिया में अनेक भागों में संयुक्त राज्य अमेरिका की अनेक सामाजिक मसौदाओं ने और सांस्कृतिक मूल्यों ने विदेशों की सम्यता एवं रहन-सहन के तरीके पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला। अमेरिका का विदेशी व्यापार बढ़ता चला गया और उसके उत्पादन की मात्रा अधिक होती गई। सम्पूर्ण यूरोप में और मध्यपूर्व

जापान, चीन, लेटिन अमेरिका तथा एशिया और अफ्रीका के अनेक राज्यों में अमेरिका द्वारा निमित्त सामान का निर्यात होने लगा ।

4 अमेरिकी पर्यटक—अमेरिकी यात्रियों की सेनाएँ भी अनेक देशों में छा गईं । यूरोप के प्रायः प्रत्येक भाग में उनका प्रवेश हो गया । इन यात्रियों द्वारा दूसरे राज्यों को जो आर्थिक लाभ होता था उसके कारण वह इन्हें पूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास कराने लगा । अमेरिकी व्यापारियों, विद्यार्थियों तथा अवकाश व्यतीत करने वालों आदि के द्वारा अमेरिकी संस्कृति का प्रसार किया गया । इन्होंने अमेरिकी विचारों एवं परम्पराओं के प्रसार द्वारा विदेशों में समुक्त राज्य अमेरिका का सम्मान और प्रभाव बढ़ाया ।

5 अमेरिकी चलचित्र—विदेशों में अमेरिकी संस्कृति के प्रभाव की वृद्धि में अमेरिकी चलचित्रों ने पर्याप्त योगदान किया । चलचित्रों के माध्यम से अमेरिका ने पेरिस और रोम, ओसलो और बर्लिन, लन्दन और मेड्रिड के मध्यम वर्गों के फैशन तथा आचार-विचारों को प्रभावित किया ।

प्रथम महायुद्ध के बाद तेजी से बदलती अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार के लिए बाध्य कर दिया । 1920 की दुनिया में जो परिस्थितियाँ थीं उनमें प्रजातन्त्र अपेक्षाकृत सुरक्षित था, किन्तु 1930 तक फासीवाद को कई जगह विजय प्राप्त हो चुकी थी तथा अन्य प्रदेशों में तानाशाही शासनो का विकास हो गया था । अब संसार सर्वाधिकारवाद के खतरे में पड़ चुका था और यह असम्भव था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस विकास से आँखें मूंद लेता । अमेरिकी नेताओं को यह विश्वास हो चला कि तटस्थता एवं पार्थक्य का अब कोई महत्त्व नहीं रह गया है । राज्य-सचिव हल का कहना था कि पृथक्तावाद कभी भी सुरक्षा का साधन नहीं बन सकता बल्कि यह तो असुरक्षा का एक फलदायक स्रोत है । यह स्पष्ट हो गया कि पृथक्तावादी नीति के अनुसरण के कारण अमेरिका को विश्व में 'महाशक्ति' का स्तर प्राप्त नहीं हो सकता था । मार्च, 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका पृथक्तावाद से अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की ओर मुड़ने लगा फिर भी अमेरिका चाहता यही था कि मित्र राष्ट्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए भी यूरोप के मामलों में यथासाध्य पृथक् रहे । 1937 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक भाषण दिया जिसे अमेरिकी विदेश-नीति में परिवर्तन का चोटक कहा जाता है । शिकागो में दिया गया यह भाषण 'क्वारेण्टीन वक्त्रता' (Quarantine Speech) के नाम से विख्यात है । इस भाषण से यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका ने अन्ततोगत्वा अहंस्तोत्र और तटस्थता की नीति से हटने का निश्चय कर लिया है और शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ सहयोग कर जर्मनी, जापान, इटली जैसे उग्र राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही का समर्थन किया है । अब अमेरिका यूरोप की राजनीति में रुचि लेने लगा । अनेक ऐसी घटनाएँ हुईं जिनसे स्पष्ट हो गया कि अमेरिका अब अन्तर्राष्ट्रीय

राजनीति से उदासीन नहीं रहना चाहता। वह एक सबल घोर सुदृढ़ देश के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है।

द्वितीय महायुद्ध काल में अमेरिका

द्वितीय महायुद्ध का विस्फोट होने पर अमेरिका में इस प्रश्न पर गम्भीर मनभेद रहा कि यह युद्ध में सम्मिलित हो या नहीं। जब 7 दिसम्बर, 1941 को जापान ने पलंहावर के अमेरिकी नौ सैनिक अड्डे पर बम वर्षा कर दी तो 8 दिसम्बर को ही अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार अब 'पुरानी दुनिया' तक सीमित युद्ध 'नई दुनिया' में भी प्रवेश कर गया और अमेरिका जैसा सबल तथा साधन-सम्पन्न राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्रों के पक्ष में मैदान में आ गया। महायुद्ध काल में अमेरिका ने अपनी महान् सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे शत्रुराष्ट्रों (जर्मनी, जापान, इटली आदि) की पराजय निश्चित हो गई। युद्ध के दौरान अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में अपने सैनिक भी भौंके, उन्हें शस्त्रास्त्र भी दिए और उनके लिए डॉलर की थैलियाँ भी खोल दी। इस सैनिक और आर्थिक सहायता ने अमेरिका का सिक्का जमा दिया और एक 'महाशक्ति' के रूप में उदय होने का उसका मार्ग प्रशस्त हो गया।

द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका एक 'महाशक्ति' के रूप में

द्वितीय महायुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रच्यवत् रूप में एक वरदान सिद्ध हुआ। प्रथम महायुद्ध ने अमेरिका को एक ऋणी राष्ट्र से ऋणदाता राष्ट्र का रूप दिया था और द्वितीय महायुद्ध ने अचिरांत विश्व को उसके आर्थिक प्रभुत्व से आन्ध्रादित कर दिया। कारण स्पष्ट था कि महायुद्ध में अमेरिका को उस घोर विनाश का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका अन्य मित्र और शत्रु-राष्ट्रों को करना पड़ा था। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस आदि सभी राष्ट्र भयंकर बमवर्षा के शिकार हुए थे और ब्रिटेन को छोड़कर इन सभी देशों की भूमि पर रक्तरेजित युद्ध हुए थे। सीमाव्यवश अमेरिका ही इस दुर्दशा से बचा रहा। न उसकी भूमि पर युद्ध लड़ा गया और न उसे दूसरे देशों के समान क्रूर बमवर्षा का शिकार होना पड़ा। इसीलिए जहाँ युद्धकाल में दूसरे देश आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से अस्त-व्यस्त हो गए, वहाँ अमेरिका की आर्थिक समृद्धि पर कोई आंच नहीं आई। युद्ध के बाद यूरोप का चित्र 'इर्दनाक' था, सैनिक दृष्टि से यूरोप के राष्ट्र अत्यधिक दुर्बल थे, आर्थिक दृष्टि से वे लगभग मौत के मुँह में थे, वहाँ अमेरिका इन सब कठिनाइयों और दुर्दशाओं से बचा हुआ था। सैनिक दृष्टि से भी वह अत्यधिक सबल था और आर्थिक दृष्टि से भी इसलिए उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बहुत बढ गई और अब वह सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों ही दृष्टियों से पूँजीवाद जगत् का नेता बन गया। युद्धकाल में उसका उत्पादन गिरने के बजाय बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत और कृषि उत्पादन में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अणु बम का रहस्य भी उसके पास था, जापान पर अणु बम गिराकर वह अपनी महान् विनाशक क्षमता का परिचय दे चुका था, अतः स्वभावतः युद्ध

से पीड़ित और ध्वस्त राष्ट्र उसके भण्डे के नीचे आ खड़े हुए और उन्होंने उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। जिस लोकतन्त्रवादी जगत् का नेतृत्व पहले ब्रिटेन के हाथों में था वह अब संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में आ गया। प्रत्येक देश उसकी सहायता पाने के लिए खालाशित था।

28 अक्टूबर, 1945 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी विदेश-नीति के जिन 'बारह सूत्रों' (Twelve Points) की घोषणा की उससे यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका अब 'नेतृत्व' से पीछे नहीं हटना चाहता। ये नीति-बिन्दु अमेरिका की महत्वाकांक्षा के प्रतीक थे जिनमें अमेरिका मानो यह कह रहा था कि उसने दुनिया को बचाने, सुधारने तथा दुनिया में अपनी सरकार स्थापित करने का ठेका ले लिया है। इन उद्देश्यों में अमेरिका के 'डॉलर साम्राज्यवाद' की गूँज थी। अमेरिका अब 'पृथक्तावादी नीति' से बिल्कुल हट चुका था अर्थात् अमेरिका ने अब राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप की नीति पर चलना शुरू कर दिया था। उसको चुनौती देने वाला एक मात्र राष्ट्र सोवियत संघ था अतः अमेरिका के नीति-निर्माताओं और प्रशासकों ने यह निश्चय कर लिया कि उनका देश प्रत्येक स्तर पर सोवियत संघ के प्रभाव और साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा। इसे 'अवरोध नीति' (Policy of Containment) की संज्ञा दी गई। इसके फलस्वरूप मार्शल योजना का निर्माण हुआ जिस पर अप्रैल, 1948 में अमेरिकी कांग्रेस ने स्वीकृति की मोहर लगा दी। 'महान्नातिक' के रूप में अमेरिका के इरादे तब और और स्पष्ट हो गए जब जनवरी, 1949 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने प्रसिद्ध 'चार सूत्री कार्यक्रम' (Four Point Programme) की घोषणा की। "चार सूत्री कार्यक्रम के फलस्वरूप अमेरिकी विदेश-नीति का कार्य विश्व-व्यापी हो गया। अब यह निश्चय किया गया कि जहाँ वही शान्ति भंग करने वाली प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमण की कार्यवाही होगी, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा।"

आर्थिक क्षेत्र में तो अमेरिका ने अपना नेतृत्व स्थापित कर ही लिया, सैनिक क्षेत्र में भी उसने स्वयं को पूरी तरह एक महान्नातिक के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक कदम उठाए। अन्य देशों के साथ सैनिक सन्धियों और पारस्परिक प्रतिकक्षा सहायता कार्यक्रम की नीति प्रारम्भ की गई जिसके फलस्वरूप अप्रैल, 1948 में 'NATO' की स्थापना हुई। इस सन्धि-मंडल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी यूरोप के साथ सैनिक गठबन्धन में बँध गया। साम्यवादी जगत् के लिए यह एक चेतावनी थी कि वह नाटो के सदस्य-देशों पर आक्रमण करने का माहस न करे। इस सन्धि ने यूरोपीय देशों को एक सुरक्षा-आवरण प्रदान किया ताकि वे अपना आर्थिक और सैनिक विकास कार्यक्रम तैयार कर सकें। इस सन्धि द्वारा अमेरिका ने यह दायित्व सम्हाल लिया कि वह साम्यवाद विरोधी किसी भी युद्ध के लिए सदैव तैयार रहेगा। 'नाटो-कार्गूला' का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। नाटो-सदस्यों को सैनिक सहायता दी गई, सदस्य-देशों में सैनिक दल स्थापित किए गए तथा विभिन्न देशों के साथ मैत्री-सन्धियाँ त्रियान्वित की गईं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी अमेरिका ने सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाना प्रारम्भ कर दिया। वह सुरक्षा परिषद् में स्म विरोधी सदस्यों का समूह बना गया और संयुक्त राष्ट्रसंघ 'महाशक्तियों के दाव-पेच का भूतल' बन गया। जब सन् 1946 में सुरक्षा परिषद् में यूनान सम्बन्धी विवाद प्रस्तुत हुआ तो अमेरिका और इस तथा उनके साथी राष्ट्र 'शीत-युद्ध' को विश्व संस्था में घसीट लाए। संयुक्त राष्ट्रसंघ पर अमेरिका का प्रभाव व्याप्त हो गया और संघ के निरीक्षण में बन्तुन अमेरिका द्वारा ही यूनान को आर्थिक और सैनिक सहायता दी गई। जब 1950 में कोरिया का गृहयुद्ध छिड़ा तो मुख्य रूप से अमेरिका के प्रयत्नों से ही सुरक्षा परिषद् ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर सैनिक हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। जुलाई, 1950 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के भण्डे के नीचे जिन 16 राष्ट्रों की संयुक्त-सैनिक कमान की स्थापना हुई उसका सेनापति अमेरिका के जनरल मैकार्थर को बनाया गया। अमेरिका की प्रबल सैनिक शक्ति के कारण ही संयुक्त राष्ट्रसंघ कोरिया-युद्ध में सफल हो सका। वास्तव में सारा युद्ध अमेरिका ने लड़ा, केवल उस पर 'लेबल' संयुक्त राष्ट्रसंघ का लगा था।

इस प्रकार आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक सभी स्तरों पर अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर आया। नहुँमुखी प्रयासों के फलस्वरूप अमेरिका का प्रभाव, क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता गया और वह 'मुक्त विश्व' (Free World) का एकछत्र नेता बन गया। आज भी अमेरिका विश्व की महाशक्ति नम्बर एक बना हुआ है।

महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय को देखने के बाद अब हम द्वितीय महायुद्धोत्तरकालीन अमेरिकी विदेश-नीति का विवेचन करेंगे। युद्धोत्तर युग में अभी तक अमेरिका की बागडोर राष्ट्रपतियों के हाथ में रही है—ट्रूमैन, आइज़नहाउवर, केंनेडी, लिण्डन बी जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, जेरोल्ड फोर्ड, जिम्मी कार्टर तथा रोनाल्ड रीगन जिन्होंने 20 जनवरी, 1981 को अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की शपथ ग्रहण की।

ट्रूमैन-युग (1945-1952)

द्वितीय महायुद्ध के बाद सन् 1952 तक के अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी विदेश-नीति की जो आधारशिलाएँ रखी वे आज भी मार्गदर्शक बनी हुई हैं। भावी राष्ट्रपतियों ने अपनी विदेश-नीतियों को समबामुक्त नए मोड़ दिए, लेकिन ट्रूमैनवालीन तत्त्व आज भी सजीव हैं। साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने का जो दृढ़ निश्चय राष्ट्रपति ट्रूमैन ने व्यक्त किया था, वही प्रयत्न भावी राष्ट्रपतियों ने किया और साम्यवाद पर प्रभुत्व रखने के लिए अभिनय कदम उठाए। विश्व-राजनीति में अमेरिकी नेतृत्व को सर्वोच्चता देने का जो प्रयत्न ट्रूमैन ने किया, वही प्रयत्न भावी राष्ट्रपति भी करते रहे हैं। ट्रूमैन काल में अमेरिका यह मानकर चला कि सोवियत संघ उसका मुख्य प्रतिद्वन्दी है और अमेरिका का भावी इतिहास

भी यही बताता है कि सोवियत संघ को प्रमुख लक्ष्य मानकर ही अमेरिका की विदेश-जान्ति बहुत कुछ संचालित होती रही है।

ट्रूमैन-युग में विदेश नीति के मुख्य चरण ये रहे—‘सहयोग और सामंजस्य की नीति’, ‘अवरोध की नीति’ ‘मैनिफेस्ट-पॉलिसी की नीति’ और ‘सुले संघर्ष का काल’।

सहयोग तथा अनुकूलता की नीति (अगस्त 1945—अगस्त 1946)

प्रारम्भ में अमेरिका ने यह सोचा कि मित्र राष्ट्रों का युद्धकालीन सहयोग शान्तिकाल में भी बना रहेगा, अतः राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ‘सहयोग और सामंजस्य की नीति’ (Policy of Co-operation and Accommodation) का अनुसरण किया। अमेरिका ने चाहा कि युद्धकालीन विनाश के चिह्नों को शीघ्रताशीघ्र मिटा दिया जाए, पराजित राष्ट्रों के साथ शान्ति-मन्थियाँ सम्पन्न की जाएँ और चारों ओर शान्ति का वातावरण पैदा कर दिया जाए। अमेरिका ने यह भी चाहा कि किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता को नंग न किया जाए और कोई भी विदेशी-शक्ति किसी देश में किसी सरकार को बलपूर्वक न थोपे पर इसका यह अर्थ नहीं है कि अमेरिका ने सभी काम पूरी ईमानदारी के साथ किए। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानता है और अमेरिका की भी विदेश-नीति इस लक्ष्य से संचालित हुई कि सोवियत संघ की तुलना में अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र का निरन्तर विस्तार होता जाए।

28 अक्टूबर, 1945 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी विदेश नीति के निम्नलिखित ‘बारह सूत्रों’ (Twelve Points) की घोषणा की—

1. अमेरिका प्रादेशिक विस्तार नहीं चाहता, वह किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा।

2. अमेरिका चाहता है कि जिन देशों से सर्वोच्च प्रभुसत्ता के अधिकार बलपूर्वक छीने गए थे, वे उन्हें वापस किए जाने चाहिए।

3. अमेरिका किसी मित्र देश में, जनता की सहमति के बिना किए गए, किसी प्रादेशिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा।

4. अमेरिका देखेगा कि स्वशासन के योग्य देशों को विदेशी हस्तक्षेप के बिना अपने शासन का स्वरूप चुनने में स्वाधीनता मिले।

5. अमेरिका अपने साथियों के साथ सहयोग करते हुए पराजित देशों में शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना के लक्ष्य पर चलेगा।

6. अमेरिका ऐसी किसी सरकार को मान्यता नहीं देगा जो विदेशी शक्ति द्वारा किसी देश पर बलपूर्वक थोपी गई हो।

7. सब देशों को अनेक देशों में से होकर गुजरने वाली नदियों तथा समुद्रों में प्रावाहमन की निर्बाध स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

8. विश्व में कच्चे माल की प्राप्ति और व्यापार में सब देशों को स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

9. पश्चिमी गोलाह्न के राज्यों को दक्ष गोलाह्न के बाहर की किसी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना पड़ोसियों की भाँति अपनी सामान्य समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

10. समूचे विश्व में दरिद्रता और अभाव को दूर करने तथा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सब देशों में पूर्ण आर्थिक सहयोग हो।

11. अमेरिका विश्व में विचार-प्रभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतन्त्रता के विस्तार के लिए प्रयत्न करेगा।

12. अमेरिका का दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रों में शान्ति स्थापित करने के लिए ऐसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की आवश्यकता है जिसके सदस्य शान्ति-प्रेमी हों और शान्ति-स्थापना के लिए आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्यवाही करने के लिए भी तैयार हों।

विश्व-शान्ति के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या घटाना शुरू कर दिया। अमेरिका को आशा थी कि रूस भी सहयोग करेगा और अनुकूल उत्तर देगा लेकिन यह आशा गलत सिद्ध हुई। अमेरिका तत्कालीन विश्व-राजनीति के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में भूल कर बैठा—प्रथम, सोवियत संघ की घातमणकारी चालें, एवं द्वितीय, एशिया महाद्वीप में शान्ति।

कुछ ही समय में सभी क्षेत्रों में यह प्रगट हो गया कि रूस और अमेरिका में किसी प्रकार का समझौता और सहयोग सम्भव नहीं है। विशेषतः पाँच क्षेत्रों में सोवियत-अमेरिका मतभेद अत्यधिक तीव्र हो गए—

- (i) जर्मनी के समीकरण का प्रश्न,
- (ii) बोल्लेण्ड में रूस द्वारा बाल्टा सम्मेलन में दिए गए वचनों के उल्लंघन की अमेरिकी शिकायत,
- (iii) इटली, हंगरी, रूमानिया-बल्गेरिया तथा फिनलैण्ड के साथ शान्ति-सन्धियों का प्रश्न,
- (iv) समुक्त-राष्ट्रसंघ तथा उसमें रूस द्वारा निषेधाधिकार के प्रयोग का प्रश्न, तथा
- (v) ईरान, टर्की और यूनान में रूसी महत्वाकांक्षाओं का प्रश्न।

इन तीव्र मतभेदों और अन्य घसहमतियों के कारण दोनों शक्ति-मुटों में 'शीतयुद्ध' (Cold War) आरम्भ हो गया। रूसी चालों से बाध्य होकर अमेरिका के विदेश-नीति-निर्माताओं ने अगस्त, 1946 के लगभग सहयोग और सामंजस्य की नीति का परित्याग कर दिया।

अवरोध की नीति (अगस्त 1946—जून 1950)

अब अमेरिका ने यह निश्चय कर लिया कि साम्यवादो प्रसार को अविलम्ब अवरुद्ध किया जाए। इस निश्चय के साथ ही 'अवरोध की नीति' (Policy of Containment) पर अमल किया जाने लगा।

‘प्रचरोध की नीति’ के सम्बन्ध में अमेरिकी विदेश-नीति के मुख्य तथ्य में थे—
ट्रूमैन सिद्धान्त—मध्य-पूर्वी क्षेत्र में यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी बनने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने इन्हें आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। इसी नीति को ‘ट्रूमैन सिद्धान्त’ (Truman Doctrine) कहा जाता है। महायुद्ध के बाद चारों ओर आर्थिक सकट की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं। यूनान, टर्की और ईरान में साम्यवादी आन्दोलन ने विशेष जोर पकड़ लिया। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत भारी आर्थिक सहायता के बल पर 1950 के अन्त तक यूनान और टर्की ने साम्यवादी दबाव से सफलतापूर्वक मुक्ति प्राप्त कर ली।

‘ट्रूमैन’ सिद्धान्त के फलस्वरूप अमेरिकी विदेश-नीति का कार्यक्षेत्र विश्व-व्यापी हो गया। इस सिद्धान्त ने अमेरिका की विदेश-नीति में मौलिक परिवर्तनों को जन्म दिया, उसे विकास की एक नई दिशा दी। माइकेल डोनेलन के शब्दों में, ‘ट्रूमैन-सिद्धान्त’ निश्चय ही सम्पूर्ण स्वतन्त्र विश्व के लिए मुनरो-सिद्धान्त था। इसने पुराने सिद्धान्त को नई परिस्थितियों के साथ आवश्यकतानुसार समायोजित कर दिया और पश्चिमी गोलार्द्ध की सीमाओं का विस्तार स्वतन्त्र विश्व की सीमाओं तक कर दिया।¹ ट्रूमैन-सिद्धान्त ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अब पृथक्तावादी नीति का परित्याग कर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की समस्याओं के प्रति सक्रिय बन गया है। यह रूस को उसकी विस्तारवादी चेष्टाओं के विरुद्ध एक चेतावनी थी, मास्को के प्रति सहयोगपूर्ण नीति का परित्याग था। यह सिद्धान्त इस तथ्य की स्वीकृति थी कि भूमध्यसागर और मध्यपूर्व में उत्पन्न हुई ‘शक्ति-शून्यता’ का रूस द्वारा लाभ उठाए जाने से पूर्व अमेरिका लाभ उठाने का इच्छुक है। इस सिद्धान्त का मूल उद्देश्य बल्कन प्रायद्वीप में रूसी प्रसार को रोकने के लिए और साथ ही रूस को घेरने के लिए यूनान और टर्की को महत्वपूर्ण सैनिक छद्मे के रूप में सुरक्षित रखना तथा मध्यपूर्व के विशाल तेल भण्डार को अपने अधिकार में रखना था। यह सिद्धान्त रूस के प्रति अमेरिकी बैमनस्य की स्थूल अभिव्यक्ति था।

ट्रूमैन सिद्धान्त को बटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आधिप और सामरिक सहायता देने की अमेरिका की नीति को साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का एक नवीन रूप कहा गया। ट्रूमैन-सिद्धान्त से संयुक्त राष्ट्रमण की स्थिति को घायात पहुँचा क्योंकि यूनान और टर्की को संघ के माध्यम से नहीं बल्कि पृथक् रूप से सहायता दी गई। स्वयं अमेरिकियों की दृष्टि में ट्रूमैन-सिद्धान्त मुनरो-सिद्धान्त का ही विकसित रूप था।

मार्शल योजना—‘प्रचरोध की नीति’ का दूसरा चरण मार्शल योजना (Marshall Plan) थी। अमेरिका के विदेशमन्त्री मार्शल ने मास्को के शान्ति-सम्मेलनों में देखा कि रूसी हर बात में घडगेबाजी की नीति अपना कर शान्ति-मन्थियों बनने में विलम्ब कर रहे हैं। मार्शल शीघ्र ही समझ गया कि रूसियों द्वारा

सन्धि-चर्चा में देर लगाने का परिणाम यूरोप में क्रान्तियों द्वारा साम्यवाद की स्थापना हो जाना है ताकि फिर समझौता करने में कठिनाई न हो। मार्शल ने इस बात पर बल दिया कि यदि अखिलम्य यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार के प्रयास न किए गए तो यह साम्यवादी हो जाएगा। प्रकट रूप में उन्होंने यही कहा कि उनके देश की नीति किसी देश अथवा मिडान्त विशेष से संपर्क की नहीं बल्कि भूख, निर्धनता, माधनहीनता और अव्यवस्था का सामना करने की है। अतः पुनर्निर्माण के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोवियत रूस को आमन्त्रित किया गया, परन्तु मास्को और उसके साथी राज्यों ने इस प्रस्ताव को अमेरिकी साम्राज्यवाद की एक नई चाल बनाकर ठुकरा दिया। पश्चिमी राष्ट्रों ने मार्शल योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। 1947 में पेरिस में 16 यूरोपीय देशों (इंग्लैंड, फ्रांस, आस्ट्रेनिया, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, नार्वे, लक्जमबर्ग, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड और टर्की) के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग-समिति (Committee of European Economic Co-operation) की स्थापना की गई और यूरोपीय पुनरुद्धार का चार वर्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया।

यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि अमेरिका यदि 13 बिलियन डॉलर की धनराशि खर्च करने को तैयार हो तो 1951 तक एक आत्मनिर्भर यूरोपीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। यह रिपोर्ट 'मार्शल योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई। 'मार्शल योजना' को, जो अप्रिष्ठ रूप से 'यूरोपीय राहत कार्यक्रम' (European Relief Programme) कहलाई, कांग्रेस ने पाम कर दिया (अप्रैल, 1948)। योजना को कार्यान्वित करने के लिए 'यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन' (Organization for Europe Economic Co-operation) की स्थापना की गई।

'मार्शल योजना' से रूस और पश्चिम का विरोध पहले की अपेक्षा और भी अधिक उग्र हो गया। इस योजना के अन्तर्गत चार वर्षों (1947-1951) में अमेरिका ने यूरोप को लगभग 11 बिलियन डॉलर की सहायता दी। इस योजना के बल पर एक ओर तो पश्चिमी यूरोप आर्थिक उत्थन और साम्यवादी आधिपत्य से बच गया तथा दूसरी ओर संयुक्तराज्य अमेरिका पाश्चात्य जगत् का सर्वमान्य नेता बन गया। अमेरिका ने यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने हुए यह भर्न लगाई कि वे अपनी सरकारों में साम्यवादी तत्त्वों का उन्मूलन कर देंगे। 'मार्शल योजना' एक प्रकार से ट्रूमैन सिद्धान्त का ही विकसित रूप थी। मार्शल योजना का प्रत्युत्तर रूस ने मिनस्कर, 1947 में 'कोमिनफोर्म' की स्थापना के रूप में दिया। आर्थिक स्तर पर साम्यवाद के अवरोध की नीति के अनुसार अमेरिका ने जर्मन अर्थव्यवस्था को भी पुनर्गठित करने का प्रयास किया।

चार-मूत्री कार्यक्रम—चीन में साम्यवाद की विजय से अमेरिका को यह आशंका हो गई कि विश्व के अल्प-विकसित देश साम्यवादी प्रचार के उत्तम क्षेत्र

सिद्ध हो सकते हैं। अतः ऐसे प्रदेशों में साम्यवाद के अवरोध के लिए 20 जनवरी, 1949 को ट्रूमैन ने 'चार-सूत्री कार्यक्रम' (Four Point Programme) की घोषणा की—

- (i) संयुक्त राष्ट्रसंघ का पूर्ण समर्थन;
- (ii) विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार के कार्य चालू रखना;
- (iii) आक्रमण के विरुद्ध स्वतन्त्रता-प्रेमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाना; एवं
- (iv) अल्प-विकसित देशों के उत्थान के लिए प्राविधिक सहायता देना।

कांग्रेस ने 1950 के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिनियम (Act for International Development) द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। रिचर्ड स्टैबिस ने शब्दों में, "यह बानून अमेरिकी विदेश-नीति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।" इस योजना द्वारा प्रथम बार तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता धीरे-धीरे बढ़ने लगी क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों की आवश्यकताएँ बहुत अधिक थी तथा इसके द्वारा अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की साधना होती थी।

नाटो : अवरोध की रणनीति—संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैनिक स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के अवरोध का प्रयत्न किया। उसने दूसरे देशों के साथ सैनिक सन्धियों और पारस्परिक प्रतिरक्षा-सहायता-कार्यक्रम (Mutual Defence Assistance Programme) प्रारम्भ किया जो अमेरिकी विदेश नीति में एक नवीन प्रयोग था। सैनिक अवरोध की व्यवस्था को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए अमेरिका द्वारा नाटो का संगठन किया गया और 4 अप्रैल, 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, आइसलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क और पुर्तगाल के बीच यह प्रथम सैनिक सन्धि सम्पन्न हो गई। यह प्रथम सन्धि थी जिसके प्रति अमेरिका ने स्वयं को वचनबद्ध किया। अमेरिका को तेजी से सैनिक सन्धियों के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि सोवियत रूस ने 1949 में ही एटम बम के रहस्यों को खोज निकाला था। रूस की इस खोज से अमेरिका के अणु शक्ति पर एकाधिकार का अन्त हो गया और उसकी सर्वोच्च शक्ति को खतरा पैदा हो गया।

खुले सघर्ष का काल (जून 1950-जुलाई 1953)

साम्यवाद का खतरा ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण सैनिक सन्धियों और प्रतिरक्षा संगठनों की दिशा में भुक्तता गया। जून, 1950 में दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण हो जाने से अमेरिकी विदेश नीति में सैनिक शक्ति का महत्व द्विगुणित हो गया। कोरिया युद्ध व जून, 1950 से जुलाई, 1953 तक चला। यह अवधि शीतयुद्ध की जगह खुले सघर्ष अथवा सक्रिय युद्ध की थी, इस अवधि में अवरोध-नीति के राजनीतिक और आर्थिक पक्ष की अपेक्षा सैनिक पक्ष को विशेष महत्व देने हुए 30 अगस्त, 1951 को अमेरिका ने विनिर्वाचन के साथ एक प्रतिरक्षा-समझौता किया, 1 मिनम्बर, 1951 को आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड के साथ एक समझौता किया और दली 8 मिनम्बर, 1951 को जापान के साथ एक प्रतिरक्षा सन्धि की।

ब्राइजनहॉवर-युग (1953-1961)

जनवरी, 1953 में 24 वर्षों में प्रथम बार एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रूप में जनरल ब्राइजनहॉवर ने ह्वाइट हाउस में प्रवेश किया। ब्राइजनहॉवर-युग में अमेरिकी विदेश नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए, केवल कुछ सामयिक परिवर्तन किए गए और ट्रूमैन-मिडलान्त की भांति ही मध्यपूर्व के लिए 'ब्राइजनहॉवर-मिडलान्त' प्रतिपादित किया गया। ब्राइजनहॉवर काल में अमेरिकी विदेश नीति का स्वरूप निम्नानुसार रहा—

- (1) यथासम्भव युद्ध का बहिष्कार किया गया।
- (2) दूसरे देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई, अमेरिका ने बर्ही भी तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनाई।
- (3) साम्यवाद के प्रसार को सीमित या समाप्त करने के लिए आधिक्य और सैनिक सन्धियों की नीति भी चालू रही।
- (4) अमेरिकी सेनाओं का प्रायुनिकीकरण किया गया, लेकिन यह आश्वासन दिया गया कि अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का दुष्टप्रयोग नहीं करेगा।
- (5) विश्व के उत्पादन और लाभकारी व्यापार को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई।
- (6) यूरोपीय एकाता को प्रोत्साहन दिया गया और पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों के साथ अधिकाधिक सहयोग की नीति अपनाई गई।
- (7) संयुक्त राष्ट्रसंघ का समर्थन करते रहने और इसका साम्यवाद के विरुद्ध एक साधन के रूप में प्रयोग करने की नीति अपनाई गई।
- (8) यात्रा-कूटनीति का अधिकाधिक विस्तार किया गया।

ब्राइजनहॉवर युग में विदेश-नीति की मुख्य घटनाएँ इस प्रकार रही—

साम्यवाद के साथ शक्ति-परीक्षण, कोरिया-युद्ध की समाप्ति—ब्राइजनहॉवर ने कोरिया में एक ओर तो पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने की और दूसरी ओर समझौते के द्वार खुले रखने की नीति अपनाई। जुलाई, 1953 में कोरिया में युद्ध-विराम हो गया, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि साम्यवादी विश्व में खुली टक्कर में निर्णायक विजय प्राप्त करना अमेरिका के लिए लगभग असम्भव है।

पश्चिमी यूरोप के एकीकरण, अणुशक्ति के नियन्त्रण आदि के प्रयत्न—पश्चिमी यूरोप को एकीकृत करने के प्रयत्न किए गए। 1954 में इतने अधिक सम्मेलन हुए कि विदेश सचिव जान फोस्टर डलेस को यात्री-राज्य-सचिव की सत्ता दी जाने लगी। इसी वर्ष पश्चिमी यूरोपीय संघ (Western European Union) की स्थापना की गई और जर्मनी को नाटो का सदस्य बना लिया गया। सोवियत संघ द्वारा 1953 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लेने के बाद दिसम्बर, 1953 में ब्राइजनहॉवर ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में अणु शक्ति पर नियन्त्रण और उसकी शान्ति के लिए प्रयोग का प्रस्ताव रखा।

साम्यवाद के अवरोध के लिए सीटो तथा बगदाद-पैक्ट की स्थापना—हिन्द चीन के घटनाचक्र से प्रभावित होकर समुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवादी चीनी प्रसार को अवरोध करने के लिए मिनम्बर, 1954 में थाईलैण्ड, फिलिपाइन्स, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड के साथ 'दक्षिणी-पूर्वी एशिया समूहिक सुरक्षा सन्धि' पर हस्ताक्षर करके सीटो (SEATO) की स्थापना की। इसी प्रकार पश्चिमी एशिया के देशों की साम्यवाद से रक्षा के लिए 1955 में बगदाद-समझौते (Bagdad Pact) का सूत्रपात हुआ। इस सैनिक सन्धि में अमेरिका सहित ब्रिटेन, टर्की, ईरान, पाकिस्तान आदि देश सम्मिलित हुए।

मध्यपूर्वी आइजनहॉवर सिद्धान्त—1956 में स्वेज के प्रश्न पर मिस्र पर अमफल आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस के पश्चिमेशिया अथवा मध्यपूर्व से हट जाने से वहाँ 'शक्तिशून्यता' पैदा हो गयी। यह आगवा हुई कि इससे अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा अतः अमेरिका ने इस 'शक्तिशून्यता' को भरना चाहा। इस क्षेत्र में साम्यवादियों का प्रसार रोकने के लिए जनवरी 1957 में आइजनहॉवर सिद्धान्त (Eisenhower Doctrine) की घोषणा की गयी जिसके आधार पर 1958 में एक कानून द्वारा अमेरिका राष्ट्रपति को मध्यपूर्व से किसी भी देश में अपनी विवेक-बुद्धि से साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए फौजें भेजने और सैनिक कार्यवाही करने का व्यापक अधिकार मिला गया। काँग्रेस ने आइजनहॉवर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकी सहायता के इच्छुक मध्यपूर्व के देशों की सहायता के लिए 200 मिलियन डॉलर की विशाल धनराशि स्वीकृत की।

आइजनहॉवर-सिद्धान्त के प्रति मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हुई—जोर्डन, लेबनान, ईराक, सऊदी अरब, पाकिस्तान आदि ने इसका स्वागत किया जबकि मिस्र, सीरिया, आदि ने इसे एक साम्राज्यवादी चाल बतलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अरब-राष्ट्रवाद को कुचलने और इजरायल को अरबों पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। सोवियत संघ ने इस सिद्धान्त को अमेरिका की आक्रामक नीति की एक कड़ी माना। भारत ने प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने इसे विदेशी हस्तक्षेप और सफट की सजा दी।

आइजनहॉवर सिद्धान्त की घोषणा के बाद शीघ्र ही अमेरिका के मामले ऐसे अवसर उत्पन्न हुए जब उसे इस सिद्धान्त के प्रयोग का मौका मिला। लेबनान और जोर्डन में इस सिद्धान्त का प्रयोग हुआ, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि में यह अधिक मफल नहीं हो सका। वास्तव में "आइजनहॉवर सिद्धान्त को मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव को रोकने में मफलता नहीं मिली, उल्टे लेबनान और जोर्डन में सैनिक हस्तक्षेप के फलस्वरूप पश्चिम-विरोधी तत्वों की प्रधानता हो गई। ईराकी क्रान्ति के फलस्वरूप मारुतो का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा।" आइजनहॉवर सिद्धान्त से समुक्त राष्ट्र मध्य की प्रतिक्रिया को भी आघात पहुँचा। यह सिद्धान्त विश्व-सन्ध्या को निर्बल बनाने वाला मिड्ड हुआ। इजरायल ने विरुद्ध अरबों के तीव्र विरोध ने भी सिद्धान्त की मफलता के मार्ग में बाधा डाली।

असफल शिखर सम्मेलन (मई 1960)—आइजनहॉवर सिद्धान्त के कारण शीत-युद्ध तीव्र हो गया, तथापि सितम्बर 1959 में सोवियत प्रधानमन्त्री ख्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा से वातावरण में पुनः सुधार हुआ। आपसी मतभेदों पर बातचीत के लिए 16 मार्च, 1960 को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस का एक शिखर सम्मेलन होना निश्चित हुआ। दुर्भाग्यवश सम्मेलन के पूर्व ही दो बड़े अपशकुन हो गए—जर्मनी सम्बन्धी विवाद, एब यू-2 विमान काण्ड। जनवरी, 1960 में पश्चिम जर्मनी के वास्तवर ने आरोप लगाया कि रूसी बलिन नर हमला कर रहे हैं। ख्रुश्चेव ने धमकी दी कि 'यदि पूर्व और पश्चिम की धार्मिक ने बलिन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया तो वह पूर्वी जर्मनी से पृथक् सन्धि कर लेगा और पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ उसकी सीमा का निर्धारण करेगा।' फरवरी, 1960 में रूस ने बलिन में एक नया सकट पैदा कर दिया। पूर्वी जर्मनी में विद्यमान पश्चिमी देशों के सैनिक मिशन को दिए जाने वाले बीसा पूर्वी जर्मन सरकार के नाम से जारी कर दिए गए जबकि अब तक ये पूर्वी जर्मनी के सोवियत अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते थे। रूस इस प्रकार पश्चिमी देशों से पूर्वी जर्मनी की सरकार को तथ्यानुसार मान्यता (De facto Recognition) दिलवाना चाहता था। अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस के दृढ़ विरोध के उपरान्त अन्त में 14 मार्च 1960 को सोवियत रूस इस बात पर राजी हो गया कि पश्चिमी देशों के सैनिक अधिकारियों को पूर्वी जर्मनी में यात्रा के लिए बीसा दिए जायेंगे उन पर 'सोवियत अधिकार क्षेत्र' (Zone of Soviet Occupation) लिखा होगा। इसके बाद फिर तनाव पैदा हुआ। पश्चिम जर्मनी ने मांग की कि पश्चिमी बलिन में इस बात पर जनमत संग्रह कराया जाए कि लोग बलिन में वर्तमान स्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं या नहीं। इसके विरोध में दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि जनमत संग्रह बलिन के दोनों भागों में हो। स्पष्ट ही इस प्रकार के सन्देहपूर्ण वातावरण का कुप्रभाव शिखर सम्मेलन पर पड़ा। शिखर सम्मेलन के मार्ग में दूसरा सबसे बड़ा अपशकुन यू-2 विमान-काण्ड का था। 5 मई 1960 को सोवियत प्रधानमन्त्री ने रोपपूर्ण शब्दों में घोषणा की कि रूस ने हवाई अड्डों की जासूसी करते हुए एक यू-2 अमेरिकी विमान को 2 मई 1960 को राकेट द्वारा नीचे गिराया गया है। इसने अमेरिका पर कटु वाक-प्रहार किए और बाद में राष्ट्रपति आइजनहॉवर की इस घोषणा ने आब में धी का काम किया कि "अमेरिका की हवाई जासूसी उड़ानें न्यायसंगत हैं और पर्नेहाबर्ग की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक हैं।" सोवियत रूस ने इस चुनौती को अपना राष्ट्रीय अपमान समझा। दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया तथापि ख्रुश्चेव ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के प्रयत्नों में चिथिलता नहीं आने देनी चाहिए और शिखर सम्मेलन में यू-2 का विषय नहीं उठाया जाएगा। किन्तु जब 16 मई को शिखर सम्मेलन आरम्भ हुआ तो सोवियत प्रधानमन्त्री ने अचानक ही यू-2 काण्ड के लिए अमेरिका की निन्दा करते हुए अश्लिष्टित माँगें पेश कर दी—

- (घ) अमेरिका को अपने उत्तेजनात्मक कार्य की निन्दा करनी चाहिए, इसके लिए क्षमा मागनी चाहिए, इस कार्य को बन्द करना चाहिए और इस काण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करना चाहिए ।
- (ख) यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रूस की दृष्टि से शिखर-सम्मेलन में अमेरिका के साथ बातचीत करना व्यर्थ है और वह इसमें भाग नहीं ले सकता ।

भाइजनहॉवर द्वारा जासूसी उडानों को भविष्य में स्थगित कर देने के आश्वासनों के बावजूद क्लूश्चेव अपनी माँग पर अड़े रहे । 17 मई को सम्मेलन आरम्भ होने पर क्लूश्चेव जब नहीं आए तो यह घोषणा कर दी गई कि "क्लूश्चेव द्वारा अपनाए गए रुख के कारण शिखर-सम्मेलन वार्ता आरम्भ करना सम्भव नहीं है ।"

कैनेडी-युग (1960-1963)

नवम्बर, 1960 में सीनेट जॉन एफ. कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने । कैनेडी को विजय डेमोक्रेटिक दल की विजय थी । कैनेडी ने कतिपय दृष्टियों से अमेरिका की विदेश नीति को नया मोड़ दिया, नई गति दी । फलतः विदेश-नीति के पुराने तत्व भी अधिक प्राणवान बन गए । कैनेडी-युग की अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य बिन्दु ये थे—

1. मसम्भों और वार्ताओं द्वारा पूर्व और पश्चिम के मतभेदों को कम किया जाए, पर साथ ही साम्यवादी खतरे के विरुद्ध साहस और दृढ़ता की नीति अपनाई जाए ।
2. विश्व में साम्यवाद के प्रतिरिक्त गरीबी और अन्य तानाशाहियों भी शत्रु हैं । अमेरिका को साम्यवाद का भुकाबला करने के साथ-साथ विश्व के धार्मिक और मौस्तकृतिक सीमा प्रदेशों की ओर भी ध्यान देना चाहिए ।
3. विश्व में डॉलर के मूल्य को सुरक्षित रखा जाए, डॉलर की साम्य में कमी न होने दी जाए ।
4. ऐसे प्रयत्न बराबर किए जाएं कि महाशक्तियाँ एक-दूसरे के निबट पाएँ तथा एक-दूसरे को समझे ।
5. दोनों गुटों के बीच विचारों के स्पष्ट आदान-प्रदान द्वारा सन्तुष्टी को मिटाया जाए ।
6. साम्यवाद को सीमित करने के लिए पूरे विश्व को, यहाँ तक कि तीव्र-दीवार के पीछे के प्रदेशों को भी राजनीतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का क्षेत्र बना दिया जाए ।
7. यथा-माध्य सहप्रतिस्पर्ध पर बल दिया जाए ।

कैनेडी-शासनकाल में अमेरिकी विदेश नीति सम्बन्धी मुख्य घटनाएँ इस प्रकार रही—

मानव-अधिकार और कैनेडी—कैनेडी ने मानव-अधिकारों के प्रति दृढ़ निष्ठा व्यक्त की और इसे अमेरिकी विदेश नीति की एक प्रेरक शक्ति बताया। 20 सितम्बर, 1963 को उन्होंने नागरिक अधिकारों के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्रसभ में विचार-विमर्श किया और आशा प्रकट की कि अमेरिका सहित विश्व के सभी राष्ट्र वर्ण-भेद, जाति-भेद आदि को मिटाकर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान सुरक्षा प्रदान करेंगे।

शान्ति और सह-अस्तित्व में विश्वास—10 जून, 1963 को अपने भाषण में कैनेडी ने शान्ति और सहअस्तित्व में विश्वास प्रकट किया। कैनेडी ने शान्ति और निःशस्त्रीकरण के प्रति रूसी रुखे को कीता नहीं, बल्कि शान्ति की दिशा में रूस के सम्भावित प्रभावों को उभारा।

पुराने मित्रों के प्रति बकादारी—रूसी-साम्यवादी व्यवस्था के प्रति सह-अस्तित्व का नारा बुलन्द करने के साथ ही कैनेडी ने बकादार मित्रों के प्रति निष्ठा रखने का भी वायदा किया। उन्होंने नाटो का आर्थिक और राजनीतिक आधार मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए तथा जर्मनी के प्रश्न पर भुक्ने से इन्कार कर दिया। जून, 1961 में ख्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक् सन्धि पर हस्ताक्षर करने की प्रमत्ती दी। लेकिन कैनेडी के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों ने रूस को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि रूस की एकपक्षीय कार्यवाही उन्हें किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। इस दृष्टि का परिणाम यह हुआ कि रूस ने अपनी प्रमत्ती को कार्यान्वित नहीं किया।

क्यूबा संकट और कैनेडी—क्यूबा के संकट द्वारा कैनेडी की विदेश-नीति की दृढ़ता स्पष्ट रूप से उभरी। क्यूबा लम्बे समय से अमेरिका का समर्थक था, लेकिन जून, 1959 में फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में हुई क्रान्ति के बाद वह रूस-समर्थक बन गया। 3 सितम्बर, 1962 को इस रूसी घोषणा ने भावी संकट का संकेत दे दिया कि वह क्यूबा की नास्त्राजवादिओं से अपनी रक्षा के लिए शस्त्रास्त्रों की पूर्ण सहायता देगा। राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा कि रूस ने क्यूबा को प्रक्षेपणास्त्रों, पनडुब्बियों तथा रॉकेट आदि से सज्जित किया है जिससे अमेरिका की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है। 16 सितम्बर, 1962 को कैनेडी ने क्यूबा की हवाई जाँच-पड़ताल के आदेश दिए जिससे पुष्टि हो गई कि वहाँ प्रक्षेपणास्त्रों का भारी जमावट हो रहा है। 23 अक्टूबर, को कैनेडी ने क्यूबा की नाकेबन्दी की घोषणा कर दी। यह आदेश रूस को स्पष्ट चेतावनी थी कि उसके शस्त्रास्त्रों से सज्जित जहाज क्यूबा नहीं पहुँच सकते अन्यथा युद्ध होगा। इस घोर संकट के समय सोवियत प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने भी बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। 23 अक्टूबर को ही ख्रुश्चेव द्वारा घोषणा की गई कि रूस क्यूबा से अपने प्रक्षेपणास्त्र वापस भेजने की आज्ञा दे रहा है और वह उस द्वीप पर स्थित सभी प्रक्षेपणास्त्र अट्टो को संयुक्त राष्ट्रसभ की देखरेख में

तुझा देने को सहमत है। कॅनेडी ने तुरन्त उत्तर दिया—'मह एके सच्चे नेता मरीखा निर्गुण है।'

कॅनेडी की दृढ़ता और तत्परता तथा स्ट्रुस्चेव के विवेक और संयम के फलस्वरूप क्यूबा-संकट से उत्पन्न अणुयुद्ध की आशंका टल गई। क्यूबा संकट के वटे व्यापक परिणाम हुए—(1) रुस-चीन के सैद्धान्तिक मतभेद बढ गए। चीन ने आरोप लगाया कि रुस अमेरिका से डर कर पीछे हटा है। (2) क्यूबा-संकट ने भाग्य पर चीन के आक्रमण को प्रेरित किया। चीन ने सोचा कि अमेरिका और रुस संघर्ष में उलझेंगे। भारत को पश्चिम से सहायता नहीं मिल सकेगी और चीन भारत के एक बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लेगा। (3) क्यूबा-संकट के निवारण के फलस्वरूप पश्चिम से भारत को तेजी से सहायता मिली तथा गुट-निरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को बल मिला।

अणु-परीक्षण-प्रतिबन्ध सन्धि, 1963—कॅनेडी और स्ट्रुस्चेव के विवेक से दोनों देशों का विरोध कम हुआ और 1963 में अणु-परीक्षण प्रतिबन्ध-सन्धि ने मारको तथा वाशिंगटन के बीच मोहरांपूर्ण वातावरण पैदा किया। कॅनेडी ने निःशस्त्रीकरण के लिए भरसक प्रयास किए। सन्धि में कुछ ही दिवस पूर्व 15 अप्रैल, 1963 को अमेरिका और रुस के बीच मोबा टेलीफोन और रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता भी हुआ।

लेटिन अमेरिका और कॅनेडी—कॅनेडी ने लेटिन अमेरिका के प्रति उदार और सँजीवनी नीति अपनाई। मार्च, 1961 में उन्होंने 'प्रगति के लिए मैत्री' का प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार अलग स्वतन्त्र देशों, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधनों और व्यक्तिगत पूँजीपतियों के साथ समुत्क्राज्य अमेरिका ने लेटिन अमेरिका के आर्थिक विकास एवं जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 20 हजार मिलियन डॉलर की सहायता तथा ऋण देने की पेशकश की। इस नीति के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका के देश आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में प्रगति करने लगे।

भारत-पाक तथा कॅनेडी—कॅनेडी ने भारत के प्रति सहायता रखते हुए भी दबाव डालने की नीति का परित्याग नहीं किया। पुनंगामी बमियों को जब भारत द्वारा मुक्त कराया गया तो सुरक्षा परिषद् में भारत के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी रोक लगा दी। भारत के विरुद्ध कश्मीर के प्रश्न का उपयोग करने का भी प्रयत्न किया गया। फिर भी कॅनेडी का रुम भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में भारत के प्रति अधिक उदार रहा। 1962 में चीनी आक्रमण के समय भारत को अतिमहत्व बिना शर्त सैनिक सहायता भेजी गई।

कॅनेडी और वियतनाम—कॅनेडी ने दक्षिणी वियतनामी सरकार को सहायता करने का निश्चय किया। 1961 में दक्षिण वियतनाम में केवल 700 के लगभग अमेरिकी सैनिक थे जिन्हें 1963 में बढ़ाकर 16,500 कर दिया गया। घन और प्रत्यक्ष-शस्त्री से भी दक्षिणी वियतनाम की दिवस सरकार की सहायता की गई।

जॉनसन-युग (1964-1968)

21 नवम्बर, 1963 को राष्ट्रपति कनेडी की हत्या के बाद तत्कालीन उप-राष्ट्रपति लिण्डन बी. जॉनसन संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और बाद में 1964 के निर्वाचन में विजय प्राप्त कर पुनः राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। जॉनसन ने एक ओर तो शीत-युद्ध के विस्तार को रोकने का प्रदर्शन किया और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उग्र और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया।

जर्मन-एकीकरण और बर्लिन सम्बन्धी प्रश्न—जर्मनी और बर्लिन के प्रश्न पर अमेरिका की नीति पूर्ववत् बनी रही। अमेरिका का कहना था कि जर्मनी के दोनो भागों और बर्लिन में स्वतन्त्र मतदान द्वारा विधान-निर्माणी सभा चुनी जाए और वह सभा एक केन्द्रीय जर्मन सरकार की स्थापना करे। वह सरकार विजेता शक्तियों के साथ सन्धि करे जिसके द्वारा पोलैण्ड एव रुम द्वारा हथियाए गए प्रदेशों का अन्तिम बँटवारा हो। इसके विपरीत सोवियन रुख भी पहले के समान ही था कि पश्चिमी देश पूर्वी जर्मनी को एक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य स्वीकार कर लें और फिर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दोनो गणराज्य अपने एकीकरण के लिए परस्पर प्रत्यक्ष बातचीत करें।

साम्प्रदायी चीन को मान्यता तथा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रश्न—जॉनसन ने भी साम्प्रदायी चीन को मान्यता देने से इन्कार कर दिया। आधिक परमाणु परीक्षण सन्धि के परवान् निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयत्नों के बावजूद कोई विशेष प्रगति नहीं की जा सकी।

यूरोपीय सुरक्षा का प्रश्न—यूरोपीय सुरक्षा की दृष्टि से भी जॉनसन के शासनकाल में अमेरिकी विदेश-नीति काफी हानिप्रद रही। डिगॉल के नेतृत्व में फ्रान्स अमेरिका के प्रभाव से निकल पड़ा। विवश होकर अमेरिका को नाटो का मुख्यालय पेरिस से हटाकर बेलजियम की राजधानी ब्रुसेल्स ले जाना पड़ा।

वियतनाम का प्रश्न—वियतनाम-युद्ध को अमेरिका ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और उत्तर-वियतनाम पर अधिकाधिक उग्र एव विनाशकारी बमबर्षा की गई। 1968 के आरम्भ से ही जब उत्तरवियतनामी सेना तथा वियतनाम छापामारों ने अमेरिकी सेना को अपमानजनक पराजये दी और अमेरिका सहित विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध का तीव्र विरोध होने लगा, तो 31 मार्च, 1968 को जॉनसन ने यह नाटकीय घोषणा की कि वियतनाम में शान्ति-वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्तर-वियतनाम पर आंशिक रूप से बमबारी बन्द कर देने के आदेश दे दिए गए हैं और आगामी चुनावों में वह राष्ट्रपति-पद के लिए प्रत्याशी नहीं बनेंगे। इस घोषणा से राजनीतिक वातावरण में एक निश्चित परिवर्तन आया।

लेटिन-अमेरिका सम्बन्धी नीति—जॉनसन-प्रशासन 'प्रगति के लिए मंत्री' कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में अमफल रहा। मौलिक नीति यही

रही कि लेटिन अमेरिका को हर तरह से अमेरिकी प्रभाव-क्षेत्र में रखा जाए। जॉनसन ने उदार नीति छोड़कर कठोर रख अपनाया।

कोरिया और प्यूब्लो-काण्ड—जॉनसन ने 'अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदार' की नीति को न केवल जारी रखा वरन् उसका कार्यक्षेत्र और भी बड़ा दिया। इस नीति में शीघ्र ही एक ऐसा सफट पैदा कर दिया जिसमें अमेरिका को बड़ा अपमानित होना पड़ा। अमेरिका के एक जासूसी पोत प्यूब्लो को 23 जनवरी, 1968 को उत्तरी कोरिया ने अपनी प्रादेशिक जल-सीमा में पकड़ लिया और अन्त में अमेरिका को निहित क्षमा-याचना करनी पड़ी।

पश्चिमी-एशिया का संकट—जून, 1967 के अरब-इजरायल संघर्ष में जॉनसन-प्रशासन ने पूर्णतः अरब-विरोधी रुख अपनाया। अमेरिका ने इस बात से अपनी अनभिज्ञता प्रकट की कि आक्रमणकारी कौन है। सुरक्षा-परिपद में अमेरिका द्वारा यह भी प्रस्ताव रखा गया कि अरब-क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी सशर्त हो। अमेरिका को सोवियत रुख का यह प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ कि इजरायल अरब-क्षेत्रों से वापस हटे और इजरायली आक्रमण की निन्दा की जाए।

अमेरिका ने अरब-राज्यों की नाराजगी मोल ले ली। अरब-देशों ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिए और अपने देश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को अविलम्ब वापस चले जाने के आदेश दे दिए। जॉनसन-प्रशासन के अरब विरोधी रुखों ने कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 25 नवम्बर, 1968 को अमेरिका ने इजरायल को अमेरिकी हथियार बेचने का भी निर्णय ले लिया।

भारत-विरोधी दृष्टिकोण—जॉनसन ने भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण को समाप्त कर दिया जो कैंनेडी ने शुरू किया था। सन् 1964 में रक्षा मन्त्री चह्वाण जब अमेरिका गए तो उन्हें कहा गया कि भारत को अपनी गुरक्षा-शक्ति प्रवर्धन ही बढ़ानी चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास की कीमत पर कुछ नहीं किया जाना चाहिए। भारत को तो यह सीख दी गई जबकि पाकिस्तान को पूर्ण रूप से अस्त्र-सज्जित किया जाता रहा। जॉनसन विपत्तनाम पर अमेरिकी वमबारी सम्बन्धी भारत की आलोचना सहन नहीं कर सके और प्रधानमन्त्री शास्त्री की अमेरिकी यात्रा स्थगित कर दी। पाकिस्तान ने वरुद्ध के रन में और फिर 1965 के युद्ध में भारत के विरुद्ध अमेरिकी हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन जॉनसन-प्रशासन का वरदहस्त पाकिस्तान के मिर पर रहा। 1967 में नागा-विद्रोही पिजो को अमेरिका में शरण दी गई और 1968 में भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बूँद-बूँद बन गई। अमेरिका के भारत विरोधी रुखों ने धुन्ध होकर अक्टूबर, 1968 में संयुक्तराष्ट्र अधिवेशन के लिए न्यूयॉर्क पहुँच कर भी श्रीमती गांधी वाशिंगटन गए बिना ही दिल्ली वापस आ गई।

सारांश में जॉनसन-शासन काल में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोणों के कारण न सिर्फ अमेरिका की बाकी हानि हुई बल्कि उसे

अपनी लोकप्रियता से भी हाथ धोना पड़ा। बाद में इस तथ्य को स्वयं जॉनसन ने भी स्वीकार किया।

निकसन-युग (1969-अगस्त 1974)

29 जनवरी, 1969 को रिचर्ड-निकसन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति बने। निकसन का कार्यकाल अमेरिका के इतिहास में क्रान्तिकारी माना जाएगा क्योंकि उन्होंने साम्यवादी जगत् में अमेरिका की नीति को एक नई दिशा प्रदान की तथा अन्य दृष्टियों से भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अमेरिकी विदेश-नीति को सुदूर बढ़ाया। सुदीर्घकाल से चला आ रहा वियतनाम-युद्ध उन्हीं के कार्यकाल में समाप्त हुआ और महाशक्ति एस के साथ निःशस्त्रीकरण वार्ताओं में काफी प्रगति हुई। पूँजीवादी और साम्यवादी जगत् में 'सह-अस्तित्व' की सम्भावनाओं को जितना अधिक बल निकसन के कार्यकाल में मिला उतना पहले कभी नहीं मिला था। दुर्भाग्यवश निकसन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर 'ईमानदार राजनेता' के रूप में नहीं उभर सके और अपने ही देश में 'वाटरगेट काण्ड' ने उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। संयुक्तराज्य अमेरिका के सम्पूर्ण इतिहास में निकसन पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें इस तरह अपमानजनक रूप से पद-त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा और आने वाले राष्ट्रपति को उन्हें क्षमा करना पड़ा।

निकसन युग में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्तराज्य अमेरिका की गतिविधि तथा विदेश-नीति के मुख्य विचार-बिन्दु इस प्रकार रखे जा सकते हैं—

यूरोप की सदभावना यात्रा—राष्ट्रपति बनने के लगभग छ सप्ताह बाद ही निकसन ने यूरोप की सदभावना यात्रा की जिसका उद्देश्य एक 'नए यूरोप' की खोज करना था। निकसन यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ वियतनाम, पश्चिमी एशिया आदि की समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान करना चाहते थे। निकसन की यात्रा पर यूरोप में कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया गया। फ्रांस में तीव्र विरोध हुआ तो पश्चिमी जर्मनी अणु-प्रसार-विरोध-सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बेल्जियम को छोड़कर हर जगह राष्ट्रपति निकसन को अमेरिका विरोधी नारों की गूँज सुनाई दी।

उत्तरी कोरिया में अमेरिकी जामूसी—'अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारी' की हिमायत निकसन प्रशासन ने भी की। उत्तरी कोरिया ने अमेरिका के एक जामूसी पिमान ई सी 121 को मार गिराया। निकसन-प्रशासन ने दम्भपूर्वक घोषणा की कि दक्षिणी कोरिया तथा प्रशांत महासागर में अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए और उत्तरी कोरिया की सैनिक तैयारियों की जानकारी के लिए अमेरिका इस प्रकार की जामूसी कार्यवाही अविविध में भी जागी रहेगा।

जर्मन-समझौते की दिशा में अमेरिकी नीति—निकसन ने जर्मनी के एकीकरण की समस्या पर यद्यपि नहीं रुख अपनाया जो जॉनसन ने अपनाया था, तथापि

3 सितम्बर, 1971 को चतुर्शक्ति बर्लिन समझौता (Four Power Berlin Settlement) सम्पन्न हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के बीच सम्पन्न हुए इस समझौते के अनुसार पश्चिमी तथा पूर्वी बर्लिन के बीच आवागमन की पूरी स्वतन्त्रता हो गई और यह निश्चय किया गया कि इस क्षेत्र में विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। सोवियत संघ को पश्चिमी बर्लिन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया। यह भी घोषणा की गई कि पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी जर्मनी का मूल भाग नहीं है, दोनों क्षेत्रों के बीच सम्बन्धों को वायम रखा जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा। जर्मन-समस्याओं पर महाशक्तियों ने जो सहयोग-पूर्ण रव्य अपनाया उसका एक शुभ परिणाम यह निकला कि संयुक्त-राष्ट्रसंघ में दोनों जर्मनियों (पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी) के लिए प्रवेश का मार्ग खुल गया और दोनों राज्यों को विश्व-संस्था की सदस्यता प्राप्त हो गई।

निकसन-प्रशासन और वियतनाम—निकसन की नीति यह थी कि एक और समझौता-वार्ता के लिए द्वार खुले रखे जाएँ और दूसरी ओर सैनिक शक्ति से उत्तरी वियतनाम को समझौता करने के लिए विवश किया जाए। उत्तरी वियतनाम अमेरिकी हवाई हमलों के आगे नहीं झुका और 26 अप्रैल, 1972 को निकसन ने घोषणा की—‘हम पराजित नहीं होंगे और न ही हम अपने मित्रों को साम्यवादी आक्रमण के समक्ष घुटने टेकने देंगे।’ सधपे और वार्ता का दौर चलता रहा और आखिर 27 जनवरी, 1973 को वियतनाम में युद्धबन्दी-समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। निकसन-प्रशासन द्वारा दक्षिणी वियतनाम को भारी आर्थिक सहायता दी जाती रही। वियतनामी युद्ध-विराम स्थायी नहीं रह सका और निकसन के जाने के कुछ ही माह बाद युद्ध पुनः भड़क उठा।

निकसन और पश्चिमी एशिया—पश्चिमी-एशिया-संकट पर निकसन का दृष्टिकोण अरब-विरोधी और इजरायल समर्थक रहा। अक्टूबर, 1973 में अरब-युद्ध में इजरायल को अमेरिका का समर्थन मिला तथापि दोनों महाशक्तियों की कूटनीतिक सरगर्मी द्वारा युद्ध-विराम सम्भव हुआ।

इजरायल के समान ही ईरान को भी अधिकाधिक युद्ध-सामग्री से लैस करने की नीति अपनाई गई। ईरान के माध्यम से अमेरिकी शस्त्रास्त्रों का भण्डार पाकिस्तान पहुँचाने का कूटनीतिक खेल खेला गया। वाशिंगटन-पिण्डी-पेकिंग धुरी के समान ही वाशिंगटन-तेहरान-पिण्डी धुरी का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में विस्फोटक स्थिति पैदा करने वाली चालें थी।

निकसन और चीन—राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता और न कोई स्थायी शत्रु। अमेरिका के शत्रु नम्बर 1 चीन के प्रति मैत्री का हाथ बढ़ाकर निकसन ने अमेरिकी कूटनीति और विदेश नीति को एक क्रान्तिकारी मोड़ दिया। निकसन ने प्रारम्भ में चीन को कुछ व्यापारिक रियायतें प्रदान कीं। एकपक्षीय मुविधायों द्वारा

निक्सन-प्रशासन ने चीन के साथ पहली किशत में व्यापारिक सम्बन्ध और दूसरी किशत में राजनीतिक तथा मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने की नीति अपनाई।

अक्तूबर, 1971 में संयुक्तराष्ट्र महासभा ने राष्ट्रवादी चीन (ताइवान) को संयुक्त राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर उसके स्थान पर जनवादी चीन (कम्युनिस्ट, चीन) को सदस्य बनाने का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतों से स्वीकार कर लिया। 26 अक्तूबर, 1971 का महासभा का यह निर्णय अमेरिका की विदेश नीति और कूटनीति की पहली बड़ी हार थी। फिर भी चीन और अमेरिका की ओर से ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए जिससे राष्ट्रपति निक्सन की चीन की सम्भावित यात्रा खटाई में पड़ जाए। अमेरिका और चीन दोनों ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में एक-दूसरे के निकट आने की नीति अपनाई। वगला देश के मुक्ति आन्दोलन और भारत-पाक संघर्ष के समय दोनों राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में और उसके बाहर पाकिस्तान का खुला समर्थन किया—कूटनीतिक स्तर पर भी और सामरिक सहायता द्वारा भी।

मार्च, 1972 में निक्सन ने पeking यात्रा की। निक्सन-चाऊ का पहला शिखर ताइवान बना जिसे अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती का दम्भ था। निक्सन ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि यदि चीनी नेता अमेरिका से सहयोग करें तो वह ताइवान की समस्या के हल में रकावट नहीं डालेगा। ताइवान को चीन का एक हिस्सा मान कर तथा ताइवान स्थित अमेरिकी फौजों और फौजी अड्डों को धीरे-धीरे हटाने की इच्छा व्यक्त करके और 'ताइवान समस्या को स्वयं सुलझाएँ' कहकर निक्सन ने चीन के प्रति अपनी भावी नीति स्पष्ट कर दी। संयुक्त विज्ञप्ति से यह प्रकट किया गया कि हिन्द-चीन, कोरिया और वियतनाम के प्रश्न पर दोनों देशों में मतभेद बरकरार रहे। विज्ञप्ति में न केवल भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रख कर उनसे कश्मीर में अपनी-अपनी सेनाओं को गुड़-बिराम रखा तक लौट जाने का आग्रह किया गया, बल्कि भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की भी धृष्टता की गई। चीन ने जम्मू-कश्मीर के लोगों ने आत्म-निर्णय के अधिकार का भी समर्थन किया। मतभेद का एक मुद्दा यह भी था कि दोनों ही देशों ने वगलादेश के द्वारे में कुछ भी नहीं कहा, मानो इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार का विश्व-शान्ति और मानवता से कोई सम्बन्ध ही नहीं था।

निक्सन-सोवियत रुस—साम्यवादी विश्व के साथ सह-अस्तित्व की नीति को बहुत-कुछ आगे बढ़ाने का श्रेय निक्सन ने प्राप्त किया। निक्सन ने मई 1972 में मास्को की यात्रा की। जो संयुक्त घोषणा प्रकाशित हुई उसमें दोनों देशों ने 'शान्तिपूर्ण सम्बन्ध' विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कहा गया कि सकट से बचने और परमाणु युद्ध से दूर रहने का अग्र्यक प्रयत्न किया जाएगा। दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि वे आपसी हितों के मामले पर विचार-विनिमय की परम्परा आगे बढ़ावेंगे और अस्त्र-परिशीलन की नई गथाबनाएँ खोजेंगे। दोनों देशों ने घोषणा की कि वे सभी राज्यों की प्रभुसत्ता को समानता का दर्जा देते हैं। दोनों

देशों के बीच अस्त्र-परिसीमन पर एक ऐतिहासिक सन्धि हुई। एक अन्तरिक्ष अभियान-सहयोग-सन्धि भी हुई जिसमें निश्चय किया गया कि दोनों देशों के उड़ाके एक साथ आकाश-बिहार करेंगे और उपलब्ध जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे। एक अन्य सैनिक सन्धि भी हुई जिसमें अमेरिका ने एक प्रकार से हथ की बढ़ी हुई नौसैनिक शक्ति को स्वीकार किया।

जून, 1973 में सोवियत नेता ब्रेझ्नेव ने अमेरिका-यात्रा की और दोनों देशों में कुछ सन्धियाँ हुईं। एक सन्धि में दोनों देशों ने संकल्प लिया कि उनमें से कोई भी परमाणु-युद्ध नहीं करेगा। एक दूसरी सन्धि परमाणु-अस्त्र-शस्त्र की सीमा और परमाणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग से सम्बन्धित थी। 27 जून, 1974 को राष्ट्रपति निक्सन मास्को यात्रा पर गए और 3 जुलाई 1974 को प्रतिप्रक्षेपास्त्र प्रणालियों तथा आक्रामक परमाणु अस्त्रों को और सीमित करने तथा भूमिगत परीक्षणों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों में एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय व्यापार-समझौता हुआ जिसे 1972 के व्यापार समझौते का पूरक बताया गया।

भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के प्रति निक्सन का दृष्टिकोण—निक्सन-प्रशासन-काल में अमेरिका का भारत-विरोधी रुख विशेष उग्र रहा और निक्सन के समय दोनों देशों के बीच सम्बन्ध जितने कटु रहे, उतने पहले कभी नहीं रहे थे। निक्सन ने भारत की न केवल आर्थिक सहायता ही रोक दी, बल्कि सैनिक साज-सामान देना भी बन्द कर दिया और हर तरह से भारत के प्रति अमैत्री प्रदर्शित की। बंगलादेश के मुक्ति-ग्रान्दोलन को कुचलने में तत्कालीन यादविया सरकार को अमेरिका और चीन का जो प्रोत्साहन मिला वह लोकतन्त्र के नाम पर बलक था। भारत-पाक युद्ध छिड़ने पर और चीन द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सहायता दिए जाने पर निक्सन-प्रशासन ने भारत को न केवल किसी प्रकार की सहायता ही देने में असमर्थता प्रकट की बल्कि बंगाल की खाड़ी में अपना शक्तिशाली नौ-बेड़ा भेजकर भारत को डराने-धमकाने की भी कोशिश की। अगस्त, 1974 में राष्ट्रपति निक्सन के पद-त्याग तक ऐसी कोई उज्ज्वल आशा न हो सकी कि निक्कट भविष्य में भारत अमेरिकी सम्बन्धों में ठोस सुधार हो सकेंगे।

फोर्ड-युग

(अगस्त 1974-1976)

निक्सन को वाटरगेट काण्ड से डूबा और 9 अगस्त, 1974 को उपराष्ट्रपति जेम्स ए. कार्लिस ने अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उसने राष्ट्रपतित्व काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रणमंच पर अमेरिका की भूमिका इस प्रकार रखी—

पश्चिमी एशिया—अरब-इजरायल समस्या के समाधान के लिए अमेरिका के विदेशमन्त्री डॉ. वीमिंगर ने अपने बूटनीतिज्ञ प्रयास जारी रखे। अगस्त 4 गिनम्बर, 1975 को डॉ. वीमिंगर मित्र और इजरायल के बीच एक अन्तर्गम

समझौता कराने में सफल हुए। पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापित करने के लिए अमेरिकी कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह परिलक्षित हुआ कि इजरायल को पूरा-पूरा समर्थन देते हुए भी उसने अरब राष्ट्रों को रोबियत सश से विभुल कर अपने विश्वास में लेने की नीति अपनाई। इस नीति की यह स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब 2 नवम्बर, 1975 को अमेरिका ने मित्र को नाभिकीय भट्टी देने के निश्चय की घोषणा की। 6 मार्च, 1976 को अमेरिका ने इजरायल से आग्रह किया कि उसे पूरा सिनायी क्षेत्र खाली कर देना चाहिए। अमेरिकी कूटनीति की एक बड़ी विजय तभी मानी गई जब 15 मार्च, 1976 को मित्र के राष्ट्रपति सादात ने सोवियत सश से अपनी मैत्री-सन्धि को रद्द कर दिया। अरब-देशों के प्रति अमेरिका ने कुछ उदार रत अवश्य अपनाया, लेकिन जब सुरक्षा-परिपद् में इजरायल विरोधी प्रस्ताव आया तो 26 मार्च, 1976 को अमेरिका के राष्ट्र-प्रतिनिधि विलियम स्कैटन ने निषेधाधिकार का प्रयोग किया। 30 मई, 1976 को मित्र और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार अमेरिका ने मित्र को 10 करोड़ 20 लाख डॉलर की सहायता देने का निश्चय किया।

वियतनाम—वियतनाम में फोर्ड-प्रशासन निक्मन के पद-चिह्नो पर चलता रहा। यह लगभग स्पष्ट हो गया कि दक्षिण वियतनाम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के हाथों में चला जाएगा। 30 अप्रैल, 1975 को अमेरिका समर्थित दक्षिण वियतनामी सरकार ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार वियतनामी युद्ध समाप्त हो गया। जन-धन के भारी बलिदान के बावजूद अमेरिका को वियतनाम से हटना पड़ा। यह महायुद्धोत्तर इतिहास में अमेरिकी विदेश-नीति की सबसे गम्भीर और सज्जाजनक पराजय थी। वियतनाम के प्रति अमेरिका का आग्रोश मिटा नहीं और अगस्त, 1975 में उसने सुरक्षा-परिपद् में निषेधाधिकार का प्रयोग कर उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम का संयुक्त राष्ट्रसभ में प्रवेश रोक दिया। हिन्द-चीन पर साम्यवादियों का पूर्ण अधिकार हो जाने के बाद अमेरिका की एक विशेष उपलब्धि यह मानी जायेगी कि वह हनोई और वाशिंगटन के बीच किसी न किसी स्तर पर सम्बन्ध बनाए रखने में सफल रहा।

पाकिस्तान को हथियार—भारत के प्रति फोर्ड-प्रशासन का दृष्टिकोण निक्मन-प्रशासन से भी एक कदम आगे बढ़ा। फरवरी, 1975 में अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर 10 वर्ष से लगी पाबन्दी को हटाने के अपने निर्णय की सूचना औपचारिक रूप से भारत सरकार को दे दी। भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई और भारतीय विदेशमन्त्री ने अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा स्थगित कर दी। इन व्यवधानों के बावजूद भारत सरकार का यह प्रयत्न रहा कि अमेरिका के साथ सम्बन्ध सुधारे जाएँ। इन आदान-प्रदान का कार्यक्रम आगे भी जारी रहा। अक्टूबर, 1975 में भारत के विदेशमन्त्री ने अमेरिका की यात्रा की। भारत सरकार ने अमेरिका को स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को उन्नत अमेरिकी हथियार मिलने से शिमला समझौते के अन्तर्गत सम्बन्धों के सामान्यीकरण की

राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की जहाँ उन्हें राज्याध्यक्ष जैसा सम्मान दिया गया। इस प्रकार चीनी नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड को यह संकेत दिया कि "चीन को फोर्ड नहीं, निक्सन चाहिए।" 9 सितम्बर, 1976 को माओ की मृत्यु और 3 नवम्बर, 1976 को फोर्ड के स्थान पर जिम्मी कार्टर की विजय के फलस्वरूप अब दोनों ही देशों में सर्वोच्च नेतृत्व बदल गया।

अमेरिका और जापान—18 नवम्बर, 1974 को फोर्ड जापान की राजधानी टोकियो पहुँचे जहाँ अमेरिकी विरोधी भावना बड़ी उग्र थी। फोर्ड का स्वागत कड़ी सुरक्षा के अन्तर्गत किया गया। उनकी अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर न तो सम्राट की उपस्थिति थी और न प्रधानमंत्री की ही। जापान को इस बात से गहरी नाराजगी थी कि एक तो ओकानावा द्वीप बहुत ही विलम्ब से और भारी हीले-हवाले के बाद सौदाया गया और दूसरे चीन की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढाने से पहले अमेरिका ने जापान को विश्वास में नहीं लिया। वार्ता के दौरान जापान ने अमेरिका से अनाज की माँग की जो अमेरिका ने स्वीकार कर ली। 1969 की सुरक्षा सन्धि को दोनों देशों के मैत्री सम्बन्धों के लिए पुनः महत्वपूर्ण बताया गया।

लैटिन अमेरिका : क्यूबा के प्रति नीति परिवर्तन—लैटिन अमेरिकी राज्यों की माँग जोर तकटती जा रही थी कि अमेरिका क्यूबा के खिलाफ अव्यावहारिक नीतियों को समाप्त करे। अमेरिका क्यूबा को अन्य देशों से अलग रखने के प्रयास में असफल रहा था। क्यूबा के साथ सम्बन्ध सुधारने का दौर निवसन काल से ही शुरू हो गया और फोर्ड के शासनकाल में अमेरिकी राज्यों के 21 सदस्यीय समूह के जुलाई, 1975 के इस प्रस्ताव का अमेरिका ने समर्थन किया कि क्यूबा पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया जाए।

फोर्ड और फ्रांस—फ्रांस ने तेल राकट के समायोजन के लिए अरब देशों पर समुक्त दबाव डालने के बजाय द्विपक्षीय आधार पर सहयोग बढ़ाने की नीति अपनायी थी, किन्तु आगे चलकर 1974 के अन्तिम चरण में जब राष्ट्रपति फोर्ड की फ्रांसीसी राष्ट्रपति गिस्तांग से भेंट हुई तो फ्रांस ने भी तेल उपभोक्ता देशों के साथ सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी।

हिन्दमहासागर में अमेरिका—हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिका अपने सैनिक साम्राज्यवाद का प्रसार करता रहा है। सभी विरोधों के बावजूद डियायोगासिया का सामरिक अड्डे के रूप में विकास किया गया।

अमेरिका 'मुक्ति संघर्षों' के विरुद्ध : महास्थितिवाद का समर्थक—अमेरिका की विदेशनीति का यह एक खेदजनक पहलू है कि उगने विश्व के राष्ट्रीय आन्दोलनों और मुक्ति संघर्षों को कभी खुले दिल से समर्थन नहीं दिया है। फोर्ड भी इसी नीति पर चले। अमेरिका रोडेजिया और दक्षिणी अफ्रीका की रणभेद समर्थक सरकारों का पक्ष लेता रहा। 30 अक्टूबर, 1974 को संयुक्त राष्ट्रसंघ से दक्षिणी अफ्रीका को निष्कासित करने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया।

कार्टर-युग (1977-1980)

20 जनवरी, 1977 को डेमोक्रेटिक पार्टी के जेम्स ब्रल कार्टर (जिम्मी कार्टर) ने अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्टर के कार्यकाल में अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रुखों को हम निम्नलिखित शीर्षकों में व्यक्त कर सकते हैं —

नये रिश्तों की शुरुआत—उपराष्ट्रपति वाल्टर माडेल को 23 जनवरी से 31 जनवरी, 1977 तक सात देशों की यात्रा पर और संयुक्तराष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि एण्ड्रू यंग को 3 से 12 फरवरी की तजानिया तथा नाइजीरिया की दस दिवसीय यात्रा पर भेजा गया। एण्ड्रू यंग ने तजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्युरेरे को विश्वास दिलाया कि हम अमेरिकी अपने प्रभाव और शक्ति के प्रयास से दक्षिण अफ्रीका भर में बहुमुखी और बहुजातीय शासन की सम्भावनाओं पर विचार कर सकते हैं। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं का समाधान अफ्रीकियों द्वारा स्वयं होना चाहिए, हम लोग तो केवल सहायता कर सकते हैं। यंग ने अफ्रीकी नेताओं को विश्वास दिलाया कि वह वायरड सशोधन में परिवर्तन कराकर रोडेशिया से श्रम का आयात बन्द करने की सिफारिश करेंगे। उपराष्ट्रपति वाल्टर माडेल ने बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान की नौ दिवसीय यात्रा में इन देशों से पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में बातचीत की। साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय और नाटो के साथ सम्बन्धों का आयोजन किया। उन्होंने इटली की जर्जर ग्रन्थव्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिलाया और नाटो के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम जर्मनी के नेताओं से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापारिक सम्झौतों पर बातचीत तथा ब्राजील को परमाणु जानकारी देने के बारे में विशेष विचार हुआ।

पश्चिमी एशिया और कार्टर प्रशासन—कार्टर प्रशासन ने पश्चिम एशिया की समस्या के निदान के लिए ध्वापेक्षा अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। 1977 में अपनी अमेरिका यात्रा पर अनेक सादात ने राष्ट्रपति कार्टर को यह बात स्पष्ट रूप से बताने दी कि जब तक फिलिस्तीनियों का पृथक् राज्य नहीं बन जाता तब तक अरब इजरायल संधि पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। यह काम केवल अमेरिका ही कर सकती है। राष्ट्रपति सादात और राष्ट्रपति कार्टर ने 1977 के उत्तरार्द्ध में जेनेवा सम्मेलन आयोजित करने के प्रयास करने की बात दोहरायी। इसके बाद ही पश्चिमी एशिया की राजनीति में तेजी से नए मोड़ आया। अक्टूबर, 1977 में अमेरिका, सीवियत संघ, अरब देश और इजरायल के बीच एक घनीपचारिक सम्मेलन हुआ जिसमें उम गतिरोध को समाप्त कर दिया जो पिछले एक वर्षों से जेनेवा सम्मेलन बुलाने में बाधक बना हुआ था। इजरायल इस बात पर सहमत हो गया कि अरब देशों के प्रतिनिधि मण्डल में फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो सकता है। कार्टर में विश्वास रखने हुए ही मादात ने सम्मेलन के

लिए इजरायल की यात्रा का ऐतिहासिक निर्णय लिया। राष्ट्रपति कार्टर दोनों पक्षों में समझौते के लिए विशेष प्रयत्न करते रहे और उन्होंने अमेरिका में कॅम्प डेविड में गिनसबर, 1978 में सादान-बेगिन-कार्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 13 दिनों का शिखर सम्मेलन 18 सितम्बर को समाप्त हुआ जबकि एक ऐतिहासिक समझौते पर कार्टर-सादान और बेगिन ने हस्ताक्षर कर दिए। समझौते की शिथिलता नहीं हो सकी क्योंकि दोनों पक्षों में कुछ मुद्दों पर मतभेद पैदा हो गए। कार्टर की प्रतिष्ठा दाब पर लग गई और अन्त में 26 मार्च 1979 को उनकी उपस्थिति में वाशिंगटन में सादान और बेगिन के हस्ताक्षरों के साथ मित्र और इजरायल में एक शान्ति सन्धि सम्पन्न हुई। यह शान्ति-सन्धि सम्पन्न कराने में सफलता प्राप्त कर अमेरिका ने वास्तव में सोवियत संघ को एक करारी वृत्तीयक मान दी। जनवरी, 1980 में अमेरिका द्वारा मित्र को 35 करोड़ डॉलर की सहायता देने का वायदा किया गया और इस प्रकार कार्टर-प्रशासन ने राष्ट्रपति सादान के प्रति अपना समर्थन जताया। मई 1980 के प्रारम्भ में फिलिस्तीनियों के अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा सुरक्षा परिषद् में वीटो का प्रयोग किया गया।

अमेरिका और क्यूबा—अमेरिका और क्यूबा में पहले से ही चर्चा या रही तनावनी 1979 के मध्य क्यूबा में रुमी सैनिकों की उपस्थिति को लेकर अचानक ही विस्फोटक स्थिति में जा पहुँची। राष्ट्रपति कार्टर ने कैरेबियन में एक अग्रिम सेना (टास्क फोर्स) तैनात करने की घोषणा कर दी। उनके साथ ही कार्टर ने कुछ नए रक्षा उपायों की भी घोषणा की। क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि क्यूबा में रुमी सैनिकों की उपस्थिति को लेकर अमेरिका के साथ हमारे जो भी विवाद हैं, हम उन पर बातचीत करने को तैयार हैं। कास्ट्रो ने कहा कि क्यूबा में जो सोवियत सैनिक हैं उनकी जानकारी तो अमेरिका को पिछले 17 वर्षों से है। सोवियत संघ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी कि क्यूबा की बात को अनावश्यक तून देकर राष्ट्रपति कार्टर आम में खेलने की जोखिम मोल न लें। स्वयं अमेरिका में भी कार्टर-प्रशासन के रूप की काफी आलोचना हुई। अन्त में कार्टर को भयना पड़ा। कार्टर ने स्वीकार किया कि इस घोर अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति दोनों देशों की सुरक्षा के लिए जवर्दमन खतरा है और क्यूबा में 2-3 हजार रुमी सैनिकों की उपस्थिति अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं बन सकती।

अमेरिका और वियतनाम—कार्टर के राष्ट्रपतित्व-काल के प्रारम्भिक कुछ महीनों में ही वियतनाम के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक बन गया। अप्रैल-मई 1977 में पेरिस तार्ता का दौरा चला। अमेरिका के रिचर्ड होल्ब्रुक ने वियतनाम दिनाया कि अमेरिका अब वियतनाम के समुक्त राष्ट्रमण का सदस्य बनने में बाधा न डालेगा। पिछली चार बार अमेरिका ने समुक्त राष्ट्रमण में अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर वियतनाम की विश्व-समस्या का सदस्य नहीं बनने दिया था। पेरिस घातों में अमेरिका ने वियतनाम से अपने दूतावास न्यायिन करने की बात उठायी। वियतनाम ने दो मुख्य बातों पर जोर दिया। पहली, अमेरिका 1973 के अमेरिका वियतनाम समझौते की 29वीं धारा के अनुसार युद्ध में प्राप्त देश के पुनर्निर्माण में अधिक सहायता दे और दूसरी, अमेरिका वियतनाम के साथ व्यापार करने पर लगाए गए सब प्रतिबन्धों को तुरन्त हटा ले।

20 सितम्बर 1977 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 32 वाँ अधिवेशन विश्व संस्था में दो नए सदस्यों के प्रवेश के साथ आरम्भ हुआ। ये सदस्य थे—वियतनाम और जिबूती।

कार्टर और भारत—जनता पार्टी के शासनकाल में भारत-अमेरिका सम्बन्धों में कुछ मुधार परिलक्षित हुआ। जनवरी 1978 के प्रथम सप्ताह में भारत-यात्रा के दौरान कार्टर ने यह घोषणा भी की कि उन्होंने तारापुर परमाणु विजली सयन्त्र के लिए श्रेष्ठ यूरेनियम की एक और खेप भेजने का प्राधिकार दे दिया है। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे दूसरों के साथ अपने विवाद सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाएँ तथा नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव के खतरे को रोकने के लिए और उनमें कमी करते हुए अन्ततः उन्हें समाप्त करने के लिए कार्य करेंगे। जून 1978 में भारत के प्रधानमन्त्री श्री देसाई संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर गए। अमेरिका के उप-विदेशमन्त्री श्री वारेन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मण्डल ने फरवरी-मार्च, 1979 में भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर लाभदायक विचार-विमर्श किया। भारतीय विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी ने 20 से 25 अप्रैल 1979 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। कुछ मसलों पर विशेषतया तारापुर सयन्त्र के नाभिकीय ईंधन की सप्लाई के बारे में दोनों देशों में मतभेद बने रहे। भारत ने स्पष्ट शब्दों में जता दिया कि संयुक्त राज्य को अपने सविदात्मक दायित्व का सम्मान करना चाहिए। श्री वाजपेयी ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि नाभिकीय हथियारों के प्रसार के निषेध के विषय में संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्देश्य से भारत सहमत है, लेकिन भारत का दृढ़ विचार है कि यदि इन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का उद्देश्य वस्तुतः नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना है तो इसे ऊँचाई तथा विस्तार दोनों प्रकार के प्रसारों पर लागू करना होगा। इससे सुरक्षा सम्बन्धी उपाय नाभिकीय हथियार नहीं रखने वाले राज्यों के साथ-साथ उन राज्यों पर भी लागू होंगे जिनके पास नाभिकीय हथियार हैं। उन्होंने यह स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि भारत ऐसे जगो भी सुरक्षा सम्बन्धी उपाय को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा जो दबाव पूर्ण हों। श्री वाजपेयी ने सुझाव दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान पर अपनी छोर से पूरी तरह से दबाव डालना चाहिए कि वह इस क्षेत्र में नाभिकीय हथियारों की होड़ शुरू करने से बाज आए। यह भी बताना दिया गया कि हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौ-सैनिक शक्ति की बढ़ोतरी के कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अन्य देशों की नौ-सैनिक उपस्थिति में वृद्धि होगी। अफगानिस्तान के मामले पर दोनों देशों के दृष्टिकोणों में अन्तर बना रहा। 24 नवम्बर, 1980 को अमेरिकी सीनेट ने भारत को परमाणु ईंधन देने का प्रस्ताव पारित करके कार्टर प्रशासन की कार्यवाही का समर्थन किया। कुछ मिलाकर कार्टर युग में भारत-अमेरिका सम्बन्ध सामान्य बने रहे।

कार्टर-प्रशासन और चीन : बदलते समीकरण—कार्टर प्रशासन चीन के साथ सम्बन्ध मुधार के लिए प्रयत्नशील रहा। अगस्त, 1977 में विदेशमन्त्री साइमन वेन

ने चीन की यात्रा की किन्तु ताइवान सम्बन्धी मतभेद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर मतैक्य नहीं हो सका। अमेरिका ताइवान से सम्बन्ध तोड़ने को तैयार नहीं हुआ और चीन के विरोधी रव्ये के कारण कार्टर ने यहाँ तक कह दिया कि चीन को पूर्ण मान्यता देने में अभी वर्षों लगेंगे। वेन्त की यात्रा की समाप्ति पर कोई सयुक्त विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गई। फिर भी ऐसा वातावरण दिखाई देने लगा कि दोनों पक्ष अन्ततः ताइवान पर समझौता कर लेंगे। वेन्त के बाद कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा मलाहकार ब्रिजिस्की ने पीकिंग की यात्रा की। चीन के प्रति नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए कार्टर ने चीन को विभिन्न किस्मों के हथियारों तथा विद्युत आणविक उपकरणों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने का निश्चय किया। अब तक ये हथियार आमतौर पर निर्यात नहीं किए जाते थे। ताइवान के प्रश्न पर अमेरिका और चीन के बीच मनभेदों की दूरी कम होती गई और मार्च, 1978 के प्रारम्भ में चीन ने अमेरिका को परामर्श दिया कि वह ताइवान से सम्बन्ध विच्छेद कर ले। 15 दिसम्बर, 1978 को राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने जनवरी, 1979 से चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की। कार्टर ने अपने वक्तव्य में यह मान लिया कि चीन केवल एक है और उसकी एक सरकार है। कार्टर ने यह अब स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका गैर-मरकारी तौर पर ताइवान से सम्बन्ध रख सकता है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि हो सकते हैं। चीन के साथ अमेरिका के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय विश्व की महत्वपूर्ण घटना मानी गई। ताइवान के साथ कोई भी सम्बन्ध रखना चीन को नागवार धा और अक्टूबर, 1980 में अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ते सम्बन्धों की चीन द्वारा पुनः आलोचना की गयी। कुल मिलाकर कार्टर के शासनकाल में अमेरिका और चीन एक दूसरे के अधिक निकट आए। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध अमेरिका और चीन ने एक स्वर से किया। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री ओहारा की स्मृति के लिए जब विभिन्न देशों के प्रमुख नेता टोकियो में एकत्रित हुए तो 10 जुलाई 1980 को कार्टर और चीनी प्रधानमंत्री हुआ की प्रथम वार्ता हुई। अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप, कम्बुजिया (कम्बोडिया) पर दियननाम का अधिकार आदि प्रश्नों पर दोनों देशों ने सहमतिपूर्ण चिन्ता व्यक्त की। कार्टर ने एक दूरदर्शन भेद वार्ता में कहा कि रूसी नैतिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, चीन और उत्पल को एक हो जाना चाहिए।

अमेरिका और रूस—कार्टर प्रशासन, वादजूद सामयिक उतार-चढ़ाव और उत्तेजनाओं के, सोवियत संघ के साथ अपने देश के उत्तरोत्तर सम्बन्ध सुधार के लिए सचेष्ट रहा। कार्टर ने अपने कार्यकाल के कुछ ही महीनों में रूस-अमेरिका सम्बन्धों का सनीकरण बदल दिया। अब तक सोवियत संघ यह मानकर चल रहा था कि वह परमाणु अस्त्रों से अग्रता प्राप्त कर लेगा और अपने यहाँ के अनन्तुष्टों का अमेरिका की प्रसन्नता के बिना दमन कर सकेगा। उसे धाया था कि इस सबके

बावजूद अमेरिका के आर्थिक सहयोग से लाभान्वित होता रहेगा। कार्टर ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमाणु अस्त्रों के बारे में वह उचित समानता चाहेगा और अमेरिका से आर्थिक सहयोग स्थापित रखने के लिए सोवियत संघ को घर में और बाहर अपना आचरण बदलना होगा। कार्टर की इस नीति ने सोवियत संघ को दुविधा में डाल दिया। निःस्त्रीकरण पर कुछ सैद्धान्तिक सहमतियों के बावजूद दोनों पक्षों में गम्भीर मतभेद बने रहे। अन्त में जून, 1979 में साल्ट-2 समझौता हो गया जिसे राजनीतिक क्षेत्र में अस्त्र-परिसीमन की दिशा में एक सीमित पर महत्वपूर्ण सन्धि मानी गई है। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को लेकर रुम-अमेरिका के बीच मुघरते सम्बन्धों में कुछ तनाव आ गया तथापि उनमें इसी स्थिति में दोनों ही महाशक्तियाँ बचने का प्रयत्न करती रही जिसमें कोई सशस्त्र टकराव हो जाए। जून, 1980 में सोवियत संघ ने यह आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की छद्मवाजी के कारण साल्ट-वार्ता की गति बहुत धीमी हो गई है।

कुल मिलाकर विदेश नीति के क्षेत्र में कार्टर अपने देश के लिए स्तुति योग्य उपलब्धियाँ हासिल नहीं कर सके और फलस्वरूप नवम्बर, 1980 के राष्ट्रपति पद के चुनावों में उन्हें रोनाल्ड रीगन के हाथों पराजित होना पड़ा।

रोनाल्ड रीगन और अमेरिकी विदेश नीति (जनवरी 1981 से अब तक)

अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर 70 वर्षीय रोनाल्ड विल्सन रीगन ने 20 जनवरी, 1981 को दोपहर को अपने पद की शपथ ग्रहण की। अपने प्रथम गन्वेश में नए राष्ट्रपति ने अमेरिका के मित्रों को आश्वासन दिया—“हम अपनी मित्रता उनकी सार्वभौमिकता पर नहीं थोपेंगे, क्योंकि हमारी अपनी सार्वभौमिकता बित्री के लिए नहीं है।” रीगन ने अमेरिका के प्रतिद्वन्द्वियों को कहा—“शान्ति में उनका यकीन है, शान्ति स्थापना के लिए वह बातचीत कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे।” जब रीगन अपना सन्देश समाप्त कर चुके तभी ईरान में अमेरिकी वन्धकों की रिहाई का समाचार प्राप्त हुआ। कार्टर सत्ते शासनकाल में किए गए अथक प्रयामों का फल सत्ता में रहते नहीं देख सके—वन्धकों को रोनाल्ड रीगन के शपथ ग्रहण से 25 मिनट पहले रिहा किया गया।

रीगन की अब तक की (मार्च, 1982 तक की) विदेश नीति कटु और कठोर रही है। मार्च, 1981 में रीगन ने कहा कि सोवियत संघ को अपने प्रभाव और हस्तक्षेप के बापरे पर प्रकुश लगाना चाहिए। रीगन ने आरोप लगाया कि सोवियत संघ और उसके समर्थक साम्राज्यवादी नीतियों को प्रथम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि—“जिस प्रकार लीबिया के मुघरर गद्दाफी चंड में बपूया के मैनिक अगोनों में, बपूया और पूर्वी जर्मनी के मैनिक द्योपिया और दक्षिण यमन में तथा अब पश्चिमी गोलार्द्ध में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे हैं उस पर रोक लगाना आवश्यक है।” रीगन ने यह बात तो दो ठूक बही कि कम्युनिस्टों को अपनी गतिविधियों के

प्रभाव को सीमित करने के लिए एक रेखा खींचनी होगी लेकिन इस बात को नजर-अन्दाज कर दिया कि स्वयं अमेरिका लेटिन अमेरिकी देशों में हस्तक्षेप बढ़ा रहा है। जुलाई, 1979 में सम्पन्न हुई निकारगुआ की सान्निहिस्ता क्रान्ति ने आसपास के गड़ोमी राष्ट्रों में एक नया जागरण पैदा किया और फलस्वरूप अलसाल्वाडोर में बिद्रोह की आग प्रज्वलित हुई। यह घटना अमेरिका साम्राज्यवाद के लिए जबरदस्त चुनौती थी। कार्टर प्रशासन ने निकारगुआ क्रान्ति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दुवार-पुचकार की कूटनीति का सहारा लिया और रीगन सरकार ने अलसाल्वाडोर को विदेश नीति का प्रथम परीक्षण स्थल बनाया। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ने घोषणा की कि अलसाल्वाडोर को क्यूबाई और सोवियत समर्थित घातकवादी पड़पन्त्र का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। 23 फरवरी, 1981 को अमेरिकी विदेश-विभाग ने एक श्वेत-पत्र में यह दावा किया कि अलसाल्वाडोर के छापामारों को क्यूबा, सोवियत गण, निकारगुआ, वियतनाम और इथियोपिया से सैनिक सहायता मिल रही है। इन आरोपों की आड़ में रीगन सरकार ने अलसाल्वाडोर में अपने हस्तक्षेप का आधार तैयार कर लिया। वास्तव में रीगन सरकार मध्य अमेरिका को साम्यवादी खतरे से बचाने के लिए 'मुनरो सिद्धान्त' की पक्षधर है। वह जरूरी मानती है कि क्यूबा को इस इलाके में मनमानी करने की आजादी नहीं दी जाए। 3 जून, 1981 को अमेरिकी कांग्रेस में एक बक्तव्य देते हुए अन्तर-अमेरिकी मामलों के उप विदेशमन्त्री टॉमस एण्डरस ने मध्य अमेरिका में क्यूबाई खतरे का मुकाबला करने के लिए चार कदमों की घोषणा की—(1) अमेरिका सक्टपस्ट राष्ट्रों को निजी सुरक्षा के लिए हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा, (2) इन राष्ट्रों को अपने आत्म-निर्णय के अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद देगा, (3) उन्हें आर्थिक सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा एवं (4) अमेरिका वर्तमान सन्ध के खत पर आक्रमण करेगा। अमेरिका ने मध्य अमेरिका और कैरिबियाई राष्ट्रों के आर्थिक पुनरोत्थान के लिए एक 'लघु मार्गल योजना' की भी घोषणा की। और इन राष्ट्रों को वकील दिलाया कि निजी लागत तथा पूँजीवादी धर्म-व्यवस्था के जरिये बेहतर आर्थिक विकास सम्भव है। वस्तुतः रीगन की मध्य अमेरिकी और कैरिबियाई नीति इन धारणा पर आधारित है कि समस्त लेटिन अमेरिका उसके प्रभाव क्षेत्र में है अतः इन इलाकों में किसी भी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप या प्रभाव को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नीति 1823 में जेम्स मुनरो द्वारा प्रतिपादित की गई थी जिसका मार यह था कि 'अमेरिका, अमेरिका के लिए है।' रीगन सरकार इस सिद्धान्त को पुनर्जीवित करना चाहती है, तभी उसने मध्य अमेरिका में अपनी सारी शक्ति लगा दी।

रीगन प्रशासन का रवैया पूर्णतः भारत-विरोधी प्रतीत होता है। रीगन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री ने अपने बधाई सन्देश में यह आशा व्यक्त की थी कि राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के सम्बन्ध निरन्तर समृद्ध होंगे। लेकिन मार्च, 1982 के अन्त तक

निराशा ही हाथ लगी। अफगानिस्तान के घटनाचक्र के बाद दोनों देशों के बीच अनेक यात्राओं का आदान-प्रदान किया गया। भारत ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए विदेश मन्त्रालय के सचिव श्री ऐरिक गोन्साल्वेज को संयुक्तराज्य की यात्रा पर भेजा। भारत ने अपना यह मत व्यक्त किया कि सोवियत सेनाओं की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए वार्ता के जरिये राजनीतिक समाधान का रास्ता खोजना होगा। पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को मजबूत करने के अमेरिका के निर्णय पर अपनी चिन्ता से भारत ने अवगत कराया और कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही से भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ेगा। उल्लेखनीय यह है कि रीगन ने सत्ताह्वल होने के कुछ ही समय बाद 22 अप्रैल, 1981 को पाकिस्तान को लगभग डार्ई अरब डॉलर के अस्त्र देने का आश्वासन दे दिया था। भारत के विरोध का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा और रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान को आधुनिकतम एफ-16 विमान देने का निर्णय कर लिया जिसका 3 दिसम्बर, 1981 को अमेरिकी सीनेट ने अनुमोदन भी कर दिया। एक अन्य समस्या जो भारत के लिए चिन्ता का विषय बनी रही, वह थी तारापुर के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई। रीगन प्रशासन ने इस सम्बन्ध में भारत-अमेरिका सम्झौते को रद्दी की टोवरी में डाल दिया और परमाणु ईंधन की सप्लाई पर रोक लगा दी। अमेरिका हिन्दमहासागरीय क्षेत्र में अपना सैनिक जमाव बराबर बढ़ाता रहा जिस पर भारत का अधिकाधिक चिन्तित होना स्वाभाविक था। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिन्दमहासागर में बड़ी शक्तियों द्वारा अपनी सैनिक उपस्थित बढ़ाने से इस क्षेत्र में तनाव निश्चय ही बढ़ेगा। रीगन के अब तक के कार्यकाल में अमेरिका-चीन सम्बन्धों में भी तनाव आया है। 16 नवम्बर, 1981 को चीन ने स्पष्ट शब्दों में धमकी दी कि यदि अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए तो वह अमेरिका से अपना राजदूत वापस बुला लेगा। पोलैण्ड के मामले को लेकर 30 दिसम्बर, 1981 को अमेरिका ने 'सोवियत सभ के विरुद्ध आधिक प्रतिबन्धों की घोषणा की, तथापि उसको अपने ही मित्र राष्ट्रों का पूरा समर्थन इस मुद्दे पर नहीं मिल पाया। रीगन प्रशासन ने शस्त्रीकरण की एन नई दौड़ शुरू कर दी है। न केवल न्यूट्रान बम के निर्माण का निर्णय लिया गया बल्कि 18 जनवरी, 1982 को राष्ट्रपति रीगन द्वारा रासायनिक अस्त्रों के निर्माण का भी समर्थन किया गया।

रीगन की नीतियों के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत में अमेरिका की दुराग्रही और साम्राज्यवादी छवि ही अधिक उभरी है ऐसा लगा। है कि एक महान् राष्ट्र अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल आचरण से परे हट रहा है।

अमेरिकी विदेश-नीति का मूल्यांकन

युद्धोत्तरकालीन अमेरिकी विदेश-नीति के विश्लेषण से मही स्पष्ट होता है कि घोषणाओं के अलावा यथार्थ में वह कभी भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोधी नहीं रहा है और यदि कभी उसने ऐसा किया भी है तो राष्ट्रीय स्वार्थों से प्रेरित होकर ही। मसल तो यह है कि आर्थिक और सैनिक महापता द्वारा अमेरिका

ने अपना एक अदृश्य साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा की है जिसमें वह काफी हद तक सफल भी हुआ है। लेटिन अमेरिका और पूर्वी एशिया उसके साम्राज्य-विस्तार के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। उसने विश्व के देशों में अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर रखे हैं तथा अनेक देशों के साथ असमान आर्थिक सैनिक समझौते किए हैं। अरब-इजरायल संघर्ष के माध्यम से उसने पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाले अपार तेल-भण्डारों पर अपना नियन्त्रण रखने की चेष्टा की है। ट्रूमैन-सिद्धान्त, आइज़नहावर सिद्धान्त, आदि इस उद्देश्य की पूर्ति के ही साधन रहे हैं। पूर्वी एशिया में भी उसने कुछ समय पूर्व तक पद-दलित शासक च्यांग-काई-शेक को चीन के शासक के रूप में मान्यता दे रही थी। वह विषयनाम और कम्बोडिया में कठपुतली सरकारों का मंचालन करता रहा है तथा पश्चिमी एशिया में इजरायल को अपनी हठधर्मों पर अड़े रहने में सहायता दे रहा है। यूरोप में वह भूतपूर्व फासिस्टों और नाज़ियों का समर्थन कर रहा है। उसके इन सब कार्यों के फलस्वरूप विश्व-शान्ति की कड़ियाँ मजबूत होने के बजाय विश्व युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण ही विकसित होता जा रहा है।

अमेरिकी विदेश नीति के अध्येता को ऐसा लगेगा मानो कि नैतिकता और विश्व-शान्ति के लिए क्या आवश्यक है। इसका निर्णय करने का ठेका केवल अमेरिका ने ही ले लिया है। एशिया में तो अमेरिकी नीति बड़ी-बड़ी गलतियों की शृंखला के अनिर्दिष्ट और कुछ नहीं है। वास्तव में अमेरिका ने एशिया की पाश्चात्य औपनिवेशिक शक्तियों के चरम से ही देखने का प्रयत्न किया है और अफ़शियायी देशों के प्रति राजनीति के निर्धारण में पुरानी दकियानूसी नीति का प्रयोग कर रहा है।

अमेरिका इस बात से परिचित है कि आज के युद्ध में युद्ध-पूर्व साम्राज्यवादी व्यवस्था को कायम नहीं किया जा सकता किन्तु वह अपने आर्थिक साम्राज्य से प्रसार की आड़ में दुनिया भर में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने को प्रयत्नशील है। विश्व के अनेक देशों में दोनों महाशक्तियों के सैनिक अड्डे कायम हैं और इस होंड में अमेरिका रुक से बहुत आगे है। अनेक उद्देश्यों के साथ अमेरिका ने असमान आर्थिक और सैनिक सन्धियों की हैं जिसके परिणामस्वरूप उन देशों को बहुत कुछ उमी नीति पर चलना पड़ता है जो अमेरिकी प्रशासन को मज़ूर हो। अमेरिका विश्व का महान् लोकतन्त्री देश है लेकिन यूरोप के फासिस्ट तत्वों का लेटिन अमेरिका के फासिस्ट शासनतन्त्र को और एशिया के सैनिकवादी राष्ट्रों को उराका पूरा समर्थन प्राप्त होना रहा है। ससार के तटस्थ और मुट-निरपेक्ष राष्ट्र उसकी आँखों के कौंटे हैं और वह अपनी अपार आर्थिक सम्पदा के बल पर उन्हें खरीद लेने का इरादा रखता है। कुल मिलाकर पिछले कुछ अर्धों से विश्व में अमेरिकी प्रतिष्ठा को घटका लगा है और विश्व के पिछड़े राष्ट्र और नवोदित स्वाधीन देश अमेरिका की अपेक्षा रुक के प्रति अधिक मैत्री भाव रखते हैं। अमेरिका के अनेक पुराने साथी भी उसकी नीति से ऊब कर उसके चंगुल से निकलने के इच्छुक हैं। एक अमेरिकी लेखक ने कुछ समय पूर्व ठीक ही टिप्पणी की थी कि—“आज एशिया और अफ़्रीका में हमारा पहचान स्वतन्त्रता के प्रतीक की हैमियन से नहीं बरन् बन्दूकों से होती है।”

व भारत के सम्बन्धों में बहुतो उन्नत हुई। अमेरिकी नेताओं का स्पष्ट कथन था कि भारत भी किन्हीं-किन्हीं दिन साम्यवादी देश बन जाएगा। उनकी दृष्टि में भारत की नीति साम्यवादी देशों का मनर्दन करती है। इस प्रकार प्रारम्भिक काल में दोनों देशों के सम्बन्ध सुधुर नहीं रहे जा सकते थे।

साम्यवादी चीन का प्रभुत्व कोरिया युद्ध तथा एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका को मान्य की आवश्यकता अनुभव हुई। अमेरिका के महासक विदेशमन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में भारत के महत्त्व को स्वीकार किया तथा घोषणा की कि पश्चिमी राष्ट्र भारत की उद्देशा नहीं कर सकते। भारत में लोकतन्त्र की महत्ता को वे अनिवार्यता समझते थे। भारत में प्रजातन्त्र की प्रसन्नता को वे एशिया में 'स्वतन्त्र विश्व' के अस्तित्व की समाप्ति मानने लगे थे। वस्तुतः भारत तथा अमेरिका में कुछ समानताएँ भी हैं। दोनों ही 'स्वतन्त्रता' तथा 'समानता' के पक्षधर हैं तथा लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों में आस्था रखते हैं। विश्व में दोनों ही प्रान्तिपूर्ण उपायों में विवादा को हल करने के समर्थक हैं। संयुक्त राष्ट्रमण्डल में दोनों ही विश्वास व्यक्त करते हैं अतः सहयोग का वातावरण बनाया गया। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की। अनेक भारतीय विद्यार्थियों को अमेरिका में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। IBRD तथा IMF से भी अमेरिका के सहित पर भारत को आर्थिक सहायता दी गई। 1960 में स्वयं राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने भारत की यात्रा की और 1961 में प नेहरू ने अमेरिका की सन्मार्चना यात्रा की। इस प्रकार एक-दूसरे के समीप आने लगे।

भारत तथा अमेरिका के मध्य सम्बन्ध सुधुर न होने का कारण यह है कि वह अपने को 'स्वतन्त्र विश्व' का मध्यस्थ नेता समझता है। भारत अपनी स्वतन्त्र नीति अपनाते को कटिबद्ध है। वह प्रत्येक विषय पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने का दृष्टिकोण है और अमेरिका का अन्ध-समर्थन करने को तैयार नहीं है। इसी कारण वह पश्चिमी राष्ट्रों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की आलोचना भी कर देता है। भारत की दृष्टि यह है कि अमेरिका उसके दृष्टिकोण को समझे तथा उसकी सहायता करे।

'गंगा मुक्ति' के लिए भारत ने सैनिक कार्यवाही की तो अमेरिका ने इसकी बहुत आलोचना की। परिणाम यह हुआ कि सद्भावना वातावरण से जो सम्बन्ध सुधरे थे वे पुनः बहुत हानि लगे। संयुक्तराज्य अमेरिका के स्थायी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की कार्यवाही की घोर निन्दा की। इससे भारत में एक भारणा प्रबल रूप से व्याप्त हो गई कि अमेरिका अभी भी साम्राज्यवादी शक्तियों का समर्थक है। 'स्वतन्त्र विश्व' की कल्पना में यदि उपनिवेशवाद सम्मिलित है तो भारत व अमेरिका के सम्बन्ध कभी भी मैत्रीपूर्ण नहीं हो सकते।

1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत ने अमेरिका से सहायता मांगी और तत्कालीन राष्ट्रपति कर्नेडी ने अखिलभ्य भारत की सहायता की। इस सहायता से दोनों देशों के मध्य पुनः सम्बन्ध सुधरने लगे। अमेरिकी सहायता तुरन्त मिल जाने में चीन की युद्ध-विराम की घोषणा करने को विवश

किया। भारत को यह आभास होने लगा कि अमेरिका साम्यवाद के विरोध में वास्तविक अर्थों में सहयोग देने को तत्पर है अतः भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया।

भारत कभी भी अमेरिका के इन घोषित आदर्शों में विश्वास नहीं कर सका कि अमेरिका प्रजातन्त्रीय देशों का समर्थक है। इसके कारण भी स्पष्ट है। भारत एक लोकतान्त्रिक देश है और पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही नियम है जो अपवाद नहीं। ऐसी स्थिति में अपने मिद्धान्त प्रेम को स्पष्ट करने के लिए अमेरिका को भारत का पक्षधर होना चाहिए था। इसके सर्वथा विपरीत प्रारम्भ से ही अमेरिका ने पाकिस्तान का ही समर्थन किया है। कश्मीर के विवाद में उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया। तास्त्व में भारत को सोवियत संघ से सम्बन्ध दृढ़ करने के लिए बिबध किया गया है। कश्मीर के प्रश्न पर सोवियत संघ ने सदैव ही भारत का समर्थन किया है। अमेरिका सदैव पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। यह सत्य है कि अमेरिका व पाकिस्तान सैनिक गठबन्धन में सहभागी हैं किन्तु घोषित उद्देश्यों के आधार पर यह गठबन्धन 'साम्यवाद को सीमित' करने के लिए है। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान ने 1965 के युद्ध में अमेरिकी शस्त्रों का प्रयोग किया था। अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में कई बार यह व्यक्त किया है कि पाकिस्तान अमेरिकी शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए अमेरिकी घोषणा का कोई अर्थ नहीं है और अमेरिका ने भी कभी इस आधार पर पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। भारत इसका क्या अर्थ लगावे? 1971 के युद्ध में भी अमेरिका ने पाकिस्तान का ही पक्ष लिया। इस बार जो स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि भारत अमेरिका से बूटनीतिक सम्बन्धों को भी समाप्त कर देना तो कोई आश्चर्य नहीं होता। युद्ध में पाकिस्तान की भर्त्सना करना तो दूर रहा अमेरिका ने बगान की साडी में अपने 7वें बेड़े (VIIth Fleet) को भी भेज दिया। भारत ने उस विषम स्थिति का इन्तर्पूर्वक सामना किया और अपने युद्ध के प्रयासों में किसी भी स्थिति में कभी नहीं घबरेला। इसी समय सोवियत संघ के नाविक बेड़े ने हिन्दमहासागर में अपनी गतिविधियाँ तीव्र कर दी। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने युद्ध जैसे कार्य का साहस नहीं किया। पाकिस्तान पराजित हुआ और अमेरिका कुछ न कर सका। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घातममर्षण किया। विश्व में इतनी विशाल मैला द्वारा घातममर्षण का विदग्ध आग्रह देखने को नहीं मिलता। इससे भारत की प्रतिष्ठा में आजातीय वृद्धि हुई और अमेरिका को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत भी एक महाशक्ति है।

अमेरिका के प्रति नीति में भारत का दृष्टिकोण सदैव स्पष्ट रहा है। भारत किसी भी दशा में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का समर्थन नहीं कर सकता। इसी आधार पर भारत ने कोरिया के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना में अपने सैनिक नहीं भेजे। भारत ने अमेरिकी नीति का विरोध किया। वियतनाम में अमेरिकी भूमिका को भारत ने बटु आलोचना की क्योंकि भारत का यह दृढ़ विश्वास था कि

प्रत्येक देश को अपनी शानत पद्धति तथा विचारधारा अपनाने का अधिकार है। भारत के दृष्टिकोण की सार्थकता इसी में सिद्ध हो जानी है कि अमेरिका को विनयनाम से हटाना पड़ा। स्वयं अमेरिका में इसका विरोध हुआ। विभक्त विनयनाम एक्ता के मून में बनाया और अमेरिका की कुचाल सकल न हो सकी। यही नहीं साम्यवाद को सीमित करने का उद्देश्य रखते हुए भी अमेरिका ने साम्यवादी चीन में मित्रता स्थापित करके यह मित्र कर दिया कि अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य साम्यवाद को सीमित करना नहीं अपितु मोक्षित सब में प्रतिद्वन्द्विता ही उनका मुख्य ध्येय है। ऐसी स्थिति में भारत उसका मित्र कैसे हो सकता है ?

भारत का दृष्टिकोण यह है कि अमेरिकी विदेश नीति साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की द्योतक है। डियागोमिसिया हिन्दमहासागर का द्वीप है। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी डियागोमिसिया में अमेरिका ने अपना नौ-मैनिक ग्रहा स्थापित कर रखा है। भारत इस ग्रह का निरन्तर विरोध कर रहा है। प्रत्येक मघ से भारत का विरोध मुखरित हो रहा है। एशिया एवं पूर्वी यूरोप के सभी शासनाध्यक्षों के साथ प्रत्येक संयुक्त विज्ञापन में डियागोमिसिया का विरोध किया जा रहा है फिर भी अमेरिका ने अपने इस ग्रह को और अधिक सुदृढ़ करने का निश्चय कर रखा है। भारत की चिन्ता यह भी है कि सोवियत नौ-सेना की गतिविधियाँ भी तीव्र हो रही हैं और हिन्दमहासागर शक्ति प्रतिद्वन्द्विता का केन्द्र बनता जा रहा है। भारत यह चाहता है कि हिन्दमहासागर शान्ति क्षेत्र बने और दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी नौसेनाओं को इस क्षेत्र से हटा लें। अमेरिका इसमें बाधक है अतः यदि भारत अमेरिका की ओर से सज्जित है तो क्या आश्चर्य है ?

भारत अणु-आयुधों का विरोधी है। वह अणुशक्ति का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण उपायों के लिए करने का पक्षधर है यद्यपि भारत ने पोखरण में अणु-विस्फोट करके अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है तद्विषय वह अपने निश्चय पर अडिग है। अमेरिका व सोवियत संघ ने आणविक शक्ति के प्रसार को रोकने के लिए Non-Proliferation Treaty की व्यवस्था की है। इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने से भारत ने इन्कार कर दिया है। भारत का तर्क यह है कि भारत अणु शस्त्रों का निर्माण करने की इच्छा नहीं रखता है फिर भी वह सन्धि पर हस्ताक्षर करने को इसलिए तत्पर नहीं है, क्योंकि यह सन्धि राष्ट्रों के मध्य समानता के आधार पर नहीं है। जिन देशों के पास अणु-आयुध नहीं है उनको सन्धि भविष्य में अणु-आयुध निर्माण करने पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था करती है किन्तु जिन देशों के पास अणु-आयुधों का भण्डार है उन्हें उन शस्त्रों को नष्ट करने के लिए विवश नहीं करती। भारत का स्पष्ट मत है कि अणु-आयुध यदि किसी भी रूप में किसी के पास न हो तो भारत को उस सन्धि पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति न होगी। भारत किसी भी वशा में पक्षपात को नहीं कर सकता। अमेरिका भारत से इस आधार पर भी अप्रसन्न है क्योंकि वह समझता है कि भारत उसकी न्यायोचित बात का भी समर्थन नहीं करता इसी कारण अमेरिका भारत को यूरेनियम देने में सानाकानी कर रहा है। भारत फिर भी

दृढ़ है और उसने घोषणा भी कर दी है कि यदि अमेरिका सन्धि के बचनों की भाँके यूरेनियम नहीं देना है तो भारत किसी अन्य स्रोत से यूरेनियम प्राप्त कर लेगा और वह भी भविष्य में उस सन्धि से बन्धा नहीं रहेगा ।

वास्तव में भारत की नीति सभी देशों के साथ मित्रता बनाए रखने की है । भारत यह मित्रता बनाए रखना अपना स्वाभिमान सुरक्षित रख कर करना चाहता है । वह किसी भी प्रकार अपने सिद्धान्तों को त्यागने को तैयार नहीं है । वह विदेश नीति के क्षेत्र में भी आदर्शों और सिद्धान्तों से प्रेरित होकर कार्य करना चाहता है । इसके लिए भारत समर्पण नहीं करेगा । उसकी यह दृढ़ता ही अमेरिका को अनुचित लगती है और वह भारत का सच्चा मित्र नहीं बन सकता ।

भारत को अमेरिका से अधिक सहायता भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है । भारत उसका सम्मान करता है किन्तु किसी भी दशा में वह अमेरिका की सम्पन्नता अथवा शक्ति के आगे नतमस्तक होने को तैयार नहीं है । भारत यह नहीं भूल पाना है कि अमेरिका सदैव पाकिस्तान को वरीयता प्रदान करता है और उसका पक्ष लेता है । इसकी नीति भारत की दृष्टि में अनुचित है तथा घोषित सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है । सिद्धान्त एवं व्यवहार में पूर्ण एकरूपता तो सम्भव नहीं है फिर भी दोनों के मध्य अन्तर यथासम्भव न्यूनतम हो यह भारत का मन है । अमेरिका अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिद्धान्तों को कोई मान्यता नहीं देता । वास्तव में उसके आदर्श मिथित सिद्धान्तों की विवेचना करने पर हमें एक ही तथ्य देखने को मिलता है वह है—सोवियत सघ विरोध और उसके प्रति प्रतिद्वन्द्विता का भाव । अतः भारत व अमेरिका के सम्बन्ध में तो कभी वास्तविक अर्थों में मित्रता के रहे हैं और न भविष्य में उसकी आशा ही करनी चाहिए । वैसे दोनों देशों को परस्पर एक-दूसरे की आवश्यकता है । साथ ही दोनों के स्वार्थों में प्रत्यक्ष टक्कर भी नहीं है अतः मित्रता के आवरण में मन्देह मर्दव व्यापता रहेगा ।



“शीतयुद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया है, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राष्ट्रों और जब वह पराकाष्ठा पर था, दो व्यक्तियों के मध्य दृढ़ संघर्ष था। विचारधाराएँ थीं पूँजोवादी और साम्यवादी; पद्धतियाँ थीं संसदीय जनतन्त्र और ‘पोपुलस’ जनतन्त्र अथवा बुर्जुआ जनतन्त्र और सर्वहारा की तानाशाही; गुट थे नाटो और धारसा-पैक्ट; राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ; तथा व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉर्स्टर डलेस।”

—के. पी. एस. मेनन

शीतयुद्ध क्या है ?

(What is Cold War ?)

द्वितीय महायुद्ध काल में अमेरिका सहित पाश्चात्य शक्तियों और सोवियत रुम में मैत्री की बुनियाद अस्थायी, परिस्थितिजन्य और सामयिक थी। महायुद्ध-काल में ही सम्भीर प्रचलित मनभेद विद्यमान थे और युद्ध के बाद तो मैत्री की सभी आशाओं में पलीला लग गया तथा दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक-दूसरे के विरुद्ध कटुवाक्याणु और आरोपों की वर्षा करने लगे। यह कहना होगा कि “बारूद के बोले-बोलियों से लड़े जाने वाले सशस्त्र मैत्रिक संघर्ष के न होते हुए भी कागज के बोलों और अक्षबारों में लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल सन्नाम छिड़ गया।” अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी सन्नाम को ‘शीतयुद्ध’ की उपाधि दी जाती है जिसमें विश्व अनेक बार भीषण मकटों में फँस चुका है और आज भी पीड़ित है। पिछले कुछ समय में शीतयुद्ध का वातावरण शिथिल दिखाई देता है, पर कोई नहीं बट सकता कि महाशक्तियों और उनके परस्पर विरोधी शिविरों में शीतयुद्ध का उबाल पुनः कब घा जाए।

अधिक स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि शीतयुद्ध में राष्ट्रों के बीच व्याप्त तनाव की एक ऐसी स्थिति होनी है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर बनाने के सभी उग्र एवं नरम कूटनीतिक दाँवपेच खेलता रहता है। दोनों पक्ष आपस में शान्तिकालीन कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रखते हुए भी शत्रु-भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक-दूसरे को दुर्बल बनाने का प्रयास करते हैं। प नेहरू के शब्दों में यह 'दिमागों में युद्ध के विचारों को प्रथम देने वाला युद्ध' है। इसका उद्देश्य शत्रुओं को झकेला पटक देना और मित्रों को जीतना होता है। यह एक ऐसा कूटनीतिक युद्ध है जो अग्नि-उग्र होने पर व्यावहारिक युद्ध का जनक हो सकता है। शीतयुद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए, सैद्धान्तिक मान्यताओं पर बल देते हुए, आर्थिक महायत्ना, प्रचार, जामूसी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक गुटबन्धियों तथा प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, शस्त्रोकरण आदि सभी सम्भव साधनों का उपयोग करते हैं।

शीतयुद्ध के कारण (Causes of Cold War)

शीतयुद्ध का आधार बहुत-कुछ महायुद्ध-काल में परोक्ष-अपरोक्ष रूप में उत्पन्न मतभेदों से ही बन चुका था। महायुद्ध के तुरन्त बाद यह मतभेद उजागर हो गए और दोनों पक्ष एक-दूसरे को अविश्वास एवं सन्देह की दृष्टि से देखने तथा एक-दूसरे पर आरोपो-प्रत्यारोपो की वर्षा करने लगे। धीरे-धीरे और भी अनेक ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिनमें शीतयुद्ध का प्रसार हुआ और दमने गहरी जड़ें जमा ली। यहाँ हम प्रारम्भिक कुछ वर्षों में शीतयुद्ध के पनपने के कारणों का उल्लेख करेंगे जिनमें 'पश्चिम' की 'पूर्व' के विरुद्ध तथा 'पूर्व' की 'पश्चिम' के विरुद्ध शिकायतें सम्मिलित हैं।

(क) पश्चिम की पूर्व के विरुद्ध शिकायतें

अमेरिका के नेतृत्व में पाश्चात्य शक्तियों ने मोस्कोविन रुम पर अनेक आरोप लगाए। उनकी मुख्य शिकायतें इस प्रकार थी—

1. इस द्वारा पाल्टा-समझौतों की अवहेलना—पाश्चात्य शक्तियों की सबसे महत्वपूर्ण शिकायत यह थी कि रुम की दृष्टि में 1945 का पाल्टा-समझौता रही कागजों के ढेर के अलावा कुछ नहीं है—

(i) रुम ने पोलेण्ड में स्वतन्त्र चुनावों पर आधारित प्रतिनिध्यात्मक सरकार की स्थापना करने की अपेक्षा पोलिश जनता पर अपने द्वारा मरिशन 'मुक्ति-सरकार' को लादने का प्रयत्न किया। साथ ही अन्य प्रजातान्त्रिक दलों को नन्दी बना लिया गया। जब अमेरिकी और ब्रिटिश प्रेक्षाओं ने पोलेण्ड में प्रवेश करना चाहा तो उनको इसकी अनुमति नहीं दी गई।

(ii) हंगरी, बल्गेरिया, रमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी रुम द्वारा युद्ध-विराम समझौतों तथा पाल्टा व पोल्मडम सन्धियों का उल्लंघन किया गया। रुम ने पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ

सहयोग करने से इन्कार कर दिया और जनमत की उपेक्षा करते हुए कम समयक मरवारों स्थापित करदी।

(11) जर्मनी द्वारा आत्म-समर्पण किए जाने से पूर्व ही रूसी फौजों ने यूनान के उत्तर में अधिकांश पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी यूरोप पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया, जनता पर साम्यवादी सरकारें थोप दी और कुछ ही वर्षों में यूनान और बाल्टिक सागर के बीच सुदृढ़ थमिक तानाशाही स्थापित हो गई।

(12) जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की सोवियत रूस की अनिच्छा और मित्रराष्ट्रों को साइबेरिया में झुंडों की सुविधा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के प्रति सन्देह और शका की वृद्धि हुई।

(13) मन्त्रिपरिषद् स्थित सोवियत फौजों ने 1946 के प्रारम्भ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहाँ प्रवेश तक नहीं करने दिया जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश सम्बन्धी सभी सुविधाएँ देकर वह सम्पूर्ण युद्ध-सामग्री भी सौंप दी जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी।

2. रूसी सेनाओं का ईरान से न हटाया जाना—युद्ध के उपरान्त एंग्लो-अमेरिकी फौजें तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, लेकिन रूसी फौजें उत्तरी ईरान में ज्यों की त्यों बनी रहीं। यद्यपि विश्व-जनमत और विश्व-संस्था के दबाव से कालान्तर में रूसी फौजें ईरान से हटायी गईं तथापि पश्चिमी राष्ट्रों को रूसी भीषण पर और भी दृढ़ सन्देह हो गया।

3. टर्की पर रूसी दबाव—युद्ध के तुरन्त बाद रूस ने टर्की से कुछ भू-प्रदेश एवं वास्कोरस में सैनिक झुंडे निमित्त करने के अधिकार की माँग की। उसके बढते हुए हस्तक्षेप के उत्तर में अमेरिका ने चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा-परिषद् में लाया जाएगा।

4. अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान—युद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व में ही प्रमुख मोघियत पत्रों में अमेरिका के प्रति बटु आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस 'प्रचार अभियान' से अमेरिका के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विश्वास फैला।

5. रूस द्वारा जर्मनी पर बोझ लादना—युद्धोपरान्त धनि-पूति-प्राप्तिके वा अनुचित लाभ उठाते हुए रूस ने जर्मन-उद्योगों को खण्डित-विखण्डित कर मूल्यवान मशीनों का स्थानान्तरण कम में करना शुरू कर दिया। रूस के इस कार्य से पहले ही से अस्त-व्यस्त जर्मन आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिरिक्त भार पड़ा। ब्रिटेन और अमेरिका में रूस की इस कार्यवाही से काफी विश्वास फँस गया और साथ ही उन्हें विवश होकर जर्मन आर्थिकव्यवस्था की सहायताएँ पर्याप्त धन व्यय करना पड़ा।

6. जर्मनी सम्बन्धी समझौते के गम्भीर उल्लंघन—रूस ने जर्मनी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के और भी अनेक गम्भीर उल्लंघन किए, जैसे (क) रूस ने अपने अधिकृत जर्मन क्षेत्र के हजारों लोगों को कैद कर रूस भेज दिया या बन्दी-जिविगो में डाल दिया, (ख) पूर्वी-जर्मनी की जनता को पश्चिमी-जर्मनी की जनता से एकदम

पृथक् कर दिया, (ग) अप्रैल, 1946 में जर्मन समाजवादी दल को बलपूर्वक साम्यवादी दल में मिला दिया गया, (घ) जर्मनी को एक पृथक् आर्थिक इकाई माने जाने सम्बन्धी व्यवस्था को ठुकराते हुए रूस ने स्पष्ट कह दिया कि प्रत्येक क्षेत्र अपना व्यापार स्वयं करे, एवं (च) रूस ने ओडर-नीसे रेखा को जर्मन-पोलिश-सीमा के रूप में मान लिया और लुबनिन सरकार को यह अनुमति प्रदान कर दी कि वह उस भूमि पर बच्चा कर वहाँ बसे जर्मन नागरिकों को बाहर निष्कासित कर दे।

7 बर्लिन की नाकेबन्दी—जून, 1948 में लन्दन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए रूस ने बर्लिन की कुर्यात नाकेबन्दी का अभियान चलाया और पश्चिम बर्लिन तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जल-यातायान बन्द कर दिया। यही नहीं, रूस ने हजारों जर्मन युद्ध-बन्दियों और नागरिकों को स्वदेश लौटने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया।

8 निषेधाधिकार का बार-बार प्रयोग—सोवियत रूस ने अपने निषेधाधिकार के अनियन्त्रित प्रयोग द्वारा समुक्त राष्ट्रसंघ के मार्ग में बाधाएँ डालना प्रारम्भ कर दिया। निषेधाधिकार के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपनाई।

9 रूस द्वारा शान्ति व्यवस्था में विघ्न—शान्ति-व्यवस्था की पुनर्स्थापना में रूस द्वारा इतनी झड़गेबाजी की गई और इतनी अनुचित तथा व्यापक माँगें प्रस्तुत की गईं कि शान्ति की समस्याएँ सुलझने के स्थान पर उलझ कर नए विवाद उत्पन्न करने लगी।

10. अमेरिका में साम्यवादी गतिविधियाँ—रूस ने अन्य देशों में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित किया। 1945 के प्रारम्भ में 'स्ट्रेटेजिक सर्विस' के अधिकारियों को पता चला कि उनकी संस्था के बहुत से गुप्त दस्तावेज साम्यवादी संरक्षण में चलने वाले 'अमेरेशिया' नामक मासिक पत्र के सम्पादक के हाथ में पहुँच गए हैं। 1946 में 'कनाडियन शाही आयोग' की रिपोर्ट ने यह प्रमाणित किया कि कनाडा का साम्यवादी दल 'सोवियत संघ की एक भुजा' है। अब अमेरिकी सरकार साम्यवादियों के प्रति पूरी तरह सजग हो गई और सम्पूर्ण अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी शक्तियों में रूस के प्रति विशोध की गहरी लहर फैल गई।

पश्चिमी राज्यों और अमेरिका ने उपर्युक्त शिकायतें कर तथा अन्य आरोप लगाकर सोवियत संघ के प्रति अपना पूर्ण अविश्वास व्यक्त कर दिया। यह कहा जाने लगा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उनके दूसरे स्वरूप की स्थापना की रोकना चाहिए। ब्रिटिश प्रधान मंत्री चर्चिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में साम्यवाद के विरोध की एक नई नीति का सत्र 5 मार्च, 1946 को अपनी मशहूर 'कुन्टन बक्तृता' में दिया। इस भाषण में चर्चिल ने यूरोप के द्वार-द्वार सोवियत 'लोह-प्रावरण' (Iron Curtain) की निन्दा की तथा स्वतन्त्रता की दीर्घाशा प्रज्ज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक ऐंग्लो-अमेरिकी

गठबन्धन की माँग की। 1946 अप्रैल मास के बाद से ही दोनों पक्षों में (पश्चिमी व पूर्वी गुट) ने अपने मतभेदों को खुलेग्राम प्रकट करना शुरू कर दिया। 12 मार्च, 1947 को यूनानी गृहयुद्ध के सम्बन्ध में कांग्रेस से यूनान एवं टर्की को 400 मिलियन डॉलर की सहायता देने का अनुरोध करते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने विख्यात 'ट्रूमैन सिद्धान्त' (Truman Doctrine) का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत उन्होंने उन सभी स्वतन्त्र देशों को सहायता देने की नीति पर बल दिया जो सशस्त्र अल्पसंख्यकों अथवा बाह्य शक्तियों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के प्रयत्नों का विरोध कर रहे थे। 5 जून, 1947 की 'मार्शल योजना' की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य यूरोप की अस्त-व्यस्त आर्थिक दशा को सुधारना था। जहाँ पाषाणयुग यूरोपीय राष्ट्रों ने इस योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, वहाँ रूस ने इसे अपने लिए गम्भीर चुनौती समझा। 3 जुलाई, 1947 को ब्रिटेन और फ्रांस ने यूरोपीय आर्थिक पुनरुत्थान की समस्या पर विचार करने के लिए पेरिस में 22 देशों के एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें प्रारम्भ में तो पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया ने भाग लेने की इच्छा प्रकट की, परन्तु बाद में सोवियत रूस के विरोध के कारण इस नियन्त्रण को ठुकरा दिया। एटली (Attlee) के शब्दों में—“जब पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया ने मार्शल सहायता के विचार को स्वीकार कर लिया तब उसकी (वेदिका की) पूर्वा और पश्चिमी यूरोप के एकीकरण की आशाएँ प्रबल हो गई; परन्तु कैमलिन के आदेश पर इन स्वीकृतियों के पश्चात् रूस ने इस आशा को नष्ट कर दिया। वस्तुतः यह 'शीत-युद्ध' की घोषणा थी।”

(ख) पूर्व (रूस) की पश्चिम के विरुद्ध शिकायतें

पश्चिमी राज्यों द्वारा रूस के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए, उससे, यह नहीं समझता चाहिए कि शीत-युद्ध के नाटक का एकमात्र खसनायक सोवियत रूस ही था। सोवियत संघ और उसके समर्थक राष्ट्रों ने अपने आरोपों में यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि युद्धोत्तर काल के तनाव और प्रशान्ति का सारा दोष पश्चिमी राष्ट्रों का है।

(i) युद्धकाल में पश्चिम द्वारा 'द्वितीय मोर्चा' खोले जाने में देरी—रूस की पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध एक सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि जर्मनी द्वारा पूरी तरह से दबे रहने की स्थिति में स्टॉलिन ने मित्रराष्ट्रों से बार-बार अनुरोध किया था कि पश्चिमी यूरोप में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोला जाए ताकि सोवियत रूस पर जर्मन-आक्रमण का दबाव कम हो, परन्तु पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा रूसी सुझाव को यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि उनकी तैयारी अभी अधूरी है। दूसरा मोर्चा खोले जाने में पर्याप्त विलम्ब किए जाने का परिणाम यह हुआ कि सोवियत रूस को जर्मनी के हाथों जन-धन की भयंकर क्षति उठानी पड़ी और रूस जनता में मित्रराष्ट्रों की नेकनीयती पर शका उत्पन्न हो गई। बैली (Bailey) के शब्दों में, “इससे कैमलिन में यह सन्देह जड़ पकड़ गया कि पश्चिमी राष्ट्र, जो युद्धोत्तर काल

में एक शक्तिशाली सोवियत मंच के उदय की सम्भावना से भयभीत हैं, युद्ध के अखाड़े में कूदने में पूर्व रुम को पूर्णतया 'आहत तथा शक्तिहीन' होते देखना चाहते हैं।"

(ii) पश्चिमी देशों की फासिस्ट देशों से सांठ-गांठ—रुम ने इस बात पर बड़ा क्षोभ प्रकट किया कि सैनिक व्यावहारिकता की आड़ में अमेरिका ने इटली और फ्रांस के फासिस्ट नरकों से सम्पर्क स्थापित किया और फिनलैण्ड द्वारा रुम के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने तथा नेनिनग्राड पर आक्रमण करने के काफी समय बाद तक वाशिंगटन ने उसमें अपने कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद नहीं किए।

(iii) युद्धकाल में पश्चिमी देशों की अपर्याप्त सहायता—सोवियत मंच ने यह आरोप लगाया कि युद्धकाल में जर्मनी द्वारा रुम पर आक्रमण होने पर पश्चिमी देशों ने जो भी सैनिक सहायता सोवियत रुस को दी, वह रुम द्वारा उत्पन्न की गई युद्ध-सामग्री का अत्यल्प अंश (केवल 4 प्रतिशत) थी। वास्तव में मिश्रराष्ट्रों की आन्तरिक इच्छा यह थी रुम जर्मनी के साथ मधुरपं में विन्कुल क्षीण हो जाए। इसीलिए उन्होंने बहुत विलम्ब से अत्यल्प मात्रा में केवल दिखावे के लिए सहायता दी।

✓(iv) अमेरिका द्वारा अणुबम के रहस्य को रुस से गुप्त रखना—अमेरिका ने अणुबम के आविष्कार को सोवियत रुम में सर्वथा गुप्त रखा, जबकि ब्रिटेन और फ्रान्स को उस बात का पता था। स्टालिन ने अमेरिका द्वारा अणुबम के रहस्य को रुम में गुप्त रखने की बात को परस्पर विश्वासघात माना। परिणामस्वरूप रुम और अमेरिका में परस्पर तनाव उत्पन्न हो गया और दोनों ही देश गुप्त रूप में वैज्ञानिक अस्त्र-ज्ञानों के आविष्कार की होड़ में मगल हो गए। रुम ने युद्ध-ममानि के बाद 4 वर्ष में ही अणुबम के रहस्य का पता लगा लिया।

✓(v) सोवियत मंच को दी जाने वाली 'लैण्ड-लीज' सहायता का बन्द किया जाना—अमेरिका द्वारा 'लैण्ड-लीज अधिनियम' (Lard Lease Act) के अन्तर्गत सोवियत मंच को जो आंशिक सहायता दी जा रही थी, उसमें वह (रुम) पहले में ही अमन्युष्ट था, क्योंकि सहायता एवढम अपर्याप्त थी; किन्तु यूरोप में विजय के उपरान्त राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जब यह आंशिक सहायता भी एकाएक बन्द कर दी तो सोवियत रुम भड़क उठा।

(vi) सोवियत विरोधी प्रचार अभियान—रुम पश्चिमी राष्ट्रों में इस बात पर भी बहुत अमन्युष्ट था कि युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार अपनी मनाफों में निरन्तर सोवियत-विरोधी माहित्य का प्रचार करती रही। पश्चिमी प्रेम खुले घाम साम्यवादी देश के प्रति घृणा-प्रचार में मगल हो गए। साम्यवादी मतों को खूब बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाने लगा और ऐसा वानावरण पैदा करने की भरमझ चपेटा की जाने लगी कि जनता में साम्यो के भावी इरादों के प्रति भय और घ्राणका की भावनाएँ व्याप्त हो जाएँ।

(vii) 5 मार्च, 1946 की चर्चन की विख्यात 'युन्टन वक्तृता' ने सोवियत रुम को एवढम बोधना दिया। इसमें इस बात का स्पष्ट निर्देश था कि "हमें

तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप को स्थापना को रोकना चाहिए।”

(viii) 'पश्चिम' के प्रति, विशेषकर संयुक्तराज्य अमेरिका के विरुद्ध रुसी सन्देशों और आशकाओं में तब आशानीत वृद्धि हो गई जब 20 सितम्बर, 1945 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति तथा तत्कालीन वाणिज्य सचिव हेनरी ए. वेलेस को केवल इस अपराध पर त्यागपत्र देने को कहा कि उसने 12 सितम्बर को न्यूयॉर्क में अपने एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच मैत्री-स्थापना की अपील की थी। इसके कुछ ही माह बाद राज्य-सचिव डीन एचीसन ने 10 फरवरी, 1947 को सीनेट के सम्मुख स्पष्ट रूप से घोषणा की कि “रूस की विदेश-नीति आनामक तथा विस्तारवादी है।” इसके बाद ही साम्यवाद के विरोध के नाम पर और सोवियत-विस्तार को रोकने के लिए ‘ट्रूमैन सिद्धान्त’, ‘मार्शल योजना’ आदि का सूत्रपात हुआ। सोवियत संघ ने इन सभी कार्यवाहियों को अपने अस्तित्व के लिए एक चुनौती माना। 25 अक्तूबर को मार्शल योजना के जवाब में यूरोप के ती-साम्यवादी देशों का कमिनिफ़र्म स्थापित किया गया। अब बात-बात पर भगडा होने लगा और एक-दूसरे के विरुद्ध गाली-गलोज और आरोपो-प्रत्यारोपो के गोले बरमाए जाने लगे।

इस विवरण से स्पष्ट है कि युद्धोत्तरकाल में ‘पूर्व’ और ‘पश्चिम’ के मध्य एक गहरी खाई खुद चुकी थी जिसके बीच सन् 1917 की सोवियत क्रान्ति से लेकर द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक के इतिहास में अच्छी तरह बौए जा चुके थे। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में ‘शीत-युद्ध’ का प्रारम्भ इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विकास था कि इसने सम्पूर्ण विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, यद्यपि इसके प्रधान केन्द्र कुछ देश ही थे।

शीतयुद्ध का इतिहास (1947-1982)

1945 से 1947 तक का काल ‘शीतयुद्ध’ के प्रारम्भ का काल था। अब हम 1947 के बाद के ‘शीतयुद्ध’ के इतिहास की प्रमुख बातों की चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्धोत्तर-काल की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्यतः ‘शीतयुद्ध’ की उपज है।

1947 से 1953 तक शीतयुद्ध

1945 से 1953 तक पश्चिमी देशों और रूस में संयुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर और बाहर अशुक्ति के नियन्त्रण व नियमन, निःशस्त्रीकरण, पराजित राष्ट्रों के साथ शान्ति-सन्धियाँ, जर्मनी, बर्लिन, यूरोपीय सुरक्षा समस्याएँ, एशिया एवं अफ्रीका के अल्पविकसित राष्ट्रों के भविष्य आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के लगभग सभी प्रश्नों पर तीव्र वाद-विवाद तथा कूटनीतिक संघर्ष चलता। रूस द्वारा मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में अक्टूबर, 1947 में यूरोप के ती-साम्यवादी देशों के ‘कमिनिफ़र्म’ की स्थापना के बाद से शीतयुद्ध की उबलता बढ़ती गई। रूस ने पूर्वी यूरोप पर

अपने नियन्त्रण की और भी अधिक कठोर बना दिया। शक्ति के दो गुट या शिविर बन गए और उनमें अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रों के विस्तार के लिए जी-सोड स्पर्धा होने लगी। रूसी दबाव के कारण फिनलैंड को मार्शल-सहायता के प्रस्ताव को अस्वीकार करना पड़ा। एक साम्यवादी देश यूगोस्लाविया ने ही अपने नेता मार्शल टीटो के नेतृत्व में स्टालिन के प्रभुत्व की स्वीकार करने से इकार कर दिया। मार्शल टीटो का यह कार्य 'शीतयुद्ध' की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी क्योंकि जहाँ इसने एक तरफ रूस-साम्यवादी देशों की नवीन बल प्रदान किया, वहाँ दूसरी तरफ रूसी दृष्टिकोण की और भी अधिक कठोर बना दिया।

बर्लिन की नाकेबन्दी, दो जर्मनियों का उदय—1948 में रूस ने बर्लिन की नाकेबन्दी कर नया सकट उत्पन्न कर दिया। इस घटना ने 'शीतयुद्ध' को एक नया मोड़ दिया। बर्लिन के घेरे के समय ही दोनों पक्षों को शक्ति-परीक्षण का सर्वप्रथम वास्तविक अवसर हाथ आया और शीतयुद्ध में इस बार अमेरिका का रूस पहली बार अत्यधिक कठोर दिखाई दिया। यद्यपि रूस की बर्लिन-नाकेबन्दी असफल मिट्ट हुई और मई, 1948 में इस नाकेबन्दी को समाप्त कर दिया गया, परन्तु इस घटना का एक गम्भीर परिणाम यह हुआ कि अब सोवियत संघ का विरोध करने के लिए अमेरिका तरह-तरह के सैनिक-संगठनों की स्थापना करने की दिशा में सज्जित हो गया। दूसरी ओर पहले से ही क्षतविक्षत जर्मनी 'शीतयुद्ध' का एक प्रधान केन्द्र बना रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनो पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। इस तरह 21 मितम्बर, 1948 को मंचीय-जर्मन-गणराज्य (Federal Republic of Germany) अथवा 'पश्चिमी जर्मनी' का उदय हुआ। मित्रराष्ट्रों अर्थात् उपर्युक्त तीनो शक्तियों में इस कार्य के प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर, 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में 'जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य' (German Democratic Republic) अथवा 'पूर्वी जर्मनी' की स्थापना कर दी गई। इस तरह पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दो जर्मन राष्ट्र अस्तित्व में आए और उनके एकीकरण का प्रश्न शीतयुद्ध को बल प्रदान करने लगा।

नाटो की स्थापना, साम्यवादो चीन का उदय, आदि घटनाएँ—रूस के कठोर रण और साम्यवाद के प्रसार की नीति का उत्तर पश्चिमी शक्तियों ने 4 अप्रैल, 1949 को 'नाटो' (NATO) की स्थापना द्वारा दिया। शीतयुद्ध का क्षेत्र केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, एशिया भी इसकी सपेट में आ गया। रूस ने टर्की और ईरान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा, परन्तु पाश्चात्य शक्तियों की महायत्ना ने ये दोनों देश रूसी दबाव का मफलतापूर्वक प्रतिरोध करते रहे। 1 अक्टूबर, 1949 को चीन में साम्यवादी गणराज्य स्थापित हो जाने से 'शीतयुद्ध' में गर्मी आ गई। साम्यवादियों की इस विजय ने रूस के उत्साह को बहुत बढ़ा दिया। समुक्त राष्ट्रमण्डल के आर्टर के अनुसार चीन गुरुता-वर्गिण का एक स्थायी सदस्य था। परन्तु जब चीनवादी शक्ति की राष्ट्रवादी सरकार पलायन कर पारमोमा चली गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महामभा एवं गुरुता-वर्गिण में अपना स्थान ग्रहण करने की

माँग की। पश्चिमी गुट यह नहीं चाहता था कि सुरक्षा-परिपद् में सोवियत संघ का एक और समर्थक हो जाए। परिपद् के 5 स्थायी सदस्यों में से 2 साम्यवादी हो जाने के डर से संयुक्तराज्य अमेरिका ने चीन की नई सरकार को मान्यता नहीं दी और साम्यवादी प्रतिनिधि के सघ में स्थान ग्रहण का घोर विरोध किया। साम्यवादी चीन की सदस्यता की माँग को इस प्रकार ठुकरा दिए जाने का रुस द्वारा तीव्र विरोध किया गया और एक बार तो उसने परिपद् की बैठकों तक का बहिष्कार कर दिया। वास्तव में साम्यवादी चीन की सघीय सदस्यता के प्रश्न पर शीतयुद्ध में कटुता और गम्भीर वैमनस्य का समावेश हुआ तथा आने वाले वर्षों में शीतयुद्ध की भीषणता और पारस्परिक मतभेदों की तीव्रता में व्यापक वृद्धि हुई। अन्त में अक्टूबर, 1971 में जनवादी चीन विश्व-मस्या का सदस्य बन पाया और सुरक्षा-परिपद् में ताइवान की जगह उसे स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई।

कोरिया का युद्ध—बलिन-प्रश्न पर और संयुक्त राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन की प्रवेश की समस्या पर शीतयुद्ध की तीव्रता अभी कम न हो पाई थी कि जून, 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया गया जिससे 'शीतयुद्ध' ने कुछ समय के लिए 'उष्ण अथवा सशस्त्र युद्ध' का रूप धारण कर लिया। प्रत्यक्ष में यह युद्ध दो कोरियाई प्रदेशों में था, परन्तु वास्तव में यह दोनों शक्ति-गुटों के नेताओं हूँ एव अमेरिका का युद्ध बन गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और उसके झण्डे के नीचे अनेक देशों की विशेषतः अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की परन्तु किसी भी पक्ष को निर्णयात्मक विजय प्राप्त न हो सकी और 8 जून, 1953 को अन्ततः कोरिया में युद्ध-विराम हो गया। प्रकट में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की सरकारों ने युद्ध बन्द हो जाने का स्वागत किया, किन्तु दलों में विद्वेष की आग घबकती रही फलतः शीतयुद्ध जारी रहा। चीन के लिए सोवियत सहायता की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई और चीन और पश्चिमी राज्यों के सम्बन्ध और भी अमैत्रीपूर्ण बन गए।

जापान के साथ मित्र देशों की शान्ति सन्धि, 1951—जिस समय कोरिया युद्ध चल रहा था, तभी मितम्बर, 1951 में अमेरिका और कई अन्य देशों ने जापान के साथ एक शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर किए। रूस को यह बान बुरी लगी और उसने इस एक्कपक्षीय कार्यवाही की खुर कर आलोचना की।

1953 से 1958 तक का शीतयुद्ध

मार्च, 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद शीतयुद्ध के इतिहास में एक नया मोड़ आया। स्टालिन का उत्तरवादी और पश्चिम के प्रति कठोर रुख 1953 के प्रारम्भ तक शीतयुद्ध का एक प्रधान कारण बना रहा। सर एलबरी गैसकोमने के अनुसार, "मई 1947 के बाद यद्यपि स्टालिन ने पश्चिमी राष्ट्रों से कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रखे, तथापि वह इतना झड़गेवाज और दुःसाध्य हो गया कि उनके साथ कार्य करना कठिन हो गया। जो भी सुझाव सामने रखे जाते वह उनको

अस्वीकार कर देता था।" स्टालिन के बाद के उत्तराधिकारी, विशेषतः ख्रुश्चेव ने समझौतावादी नीति को अपनाने की कोशिश की, अमेरिका के नेतृत्व में भी परिवर्तन आया और शीतयुद्ध के समर्थक राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर जनरल आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगस्त, 1953 में सोवियत संघ का प्रथम आणविक परीक्षण हुआ और हथियारों की विद्यमान खाई को धीरे-धीरे पाटने की दोनों की आवश्यकता महसूस होने लगी।

परन्तु शीतयुद्ध की यह शिथिलता एकदम अल्पकालिक ही थी क्योंकि रूस के विदेश-मन्त्री मोलोटोव और अमेरिका के विदेश सचिव डेलोस दोनों ही शीतयुद्ध के बाँके पटेबाज थे। एक तरफ तो हिन्द-चीन के प्रश्न पर शीतयुद्ध में पुन तेजी आ गई क्योंकि फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले युद्ध में दोनों ही गुटों ने अलग-अलग पक्षों का जोरदार समर्थन किया और दूसरी तरफ अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सैनिक समझौते तथा सैन्य संगठनों की स्थापना करने की नीति को अपनाकर शीतयुद्ध को बढावा दिया। अमेरिका ने नाटो, सीटो और बगदाद-पैक्ट स्थापित किए और इनके जवाब में रूस ने वारसा पैक्ट कायम किया। वास्तव में दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी कार्यवाहियों से एक-दूसरे के प्रति सन्देहों को दृढ़ बनाया तथा अपनी प्रत्येक कार्यवाही से शीतयुद्ध को कुछ-न-कुछ बढावा दिया। रूस ने जब पश्चिमी देशों के अनाग्रमण प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो मार्च, 1954 में जब रूसी विदेश मन्त्री मोलोटोव ने रूस ने उत्तर अटलांटिक सन्धि में सम्मिलित होने के लिए तत्परता दिखाई तो नाटो देशों ने इसका विरोध किया। जनवरी, 1956 में रूसी प्रधान मन्त्री बुल्गानिन ने राष्ट्रपति आइजनहावर के सम्मुख एक रूस-अमेरिकी सैन्य सन्धि का प्रस्ताव रखा, परन्तु वह भी फलीभूत नहीं हुआ। ऐसे प्रस्ताव समय-समय पर किए जाते रहे, किन्तु पारस्परिक मतभेद और सन्देह इतने गहरे थे कि कोई सफलता प्राप्त न हो सके। संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व आदि सभी देशों में पूर्व और पश्चिम का सघर्ष हावी रहा। जापान और जर्मनी के पुन. शस्त्रीकरण ने दोनों ही गुटों में काफी तनाव उत्पन्न कर दिया। जर्मनी के भविष्य और बर्लिन के स्तर पर भी मतभेद दूर न हो सके और न अणुशक्ति के निर्माण और नियन्त्रण पर ही कोई समझौता हो सका। समार के सबसे प्रमुख प्रश्न 'नि शस्त्रीकरण' पर दोनों ही गुटों में तीव्र मतभेद रहा—प्रस्ताव व प्रति-प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते रहे, किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक प्रश्न पर दोनों गुटों के दृष्टिकोण शीत-युद्ध की पृष्ठभूमि में निर्धारित होने लगे।

1956 में हंगरी के प्रश्न ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और शीतयुद्ध में परास्पर अभिवृद्धि की। पश्चिमी देशों ने रूसी कार्यवाही की बटु निन्दा की और उपर रूस ने स्वतंत्र नहर के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप 1956 में मिश्र पर होने वाले एण्टो-फोन्स-इजरायल आक्रमण की तीव्र भर्त्सना की। जून में 'आइजनहावर-निदान' की घोषणा के बाद मध्यपूर्व में 'शीतयुद्ध' में काफी गर्मी आ गयी। 1955 में 1958

तक पश्चिमी एशिया शीतयुद्ध का अलाड़ा बना रहा। उस क्षेत्र के सामरिक महत्त्व और तेल-कूपों पर प्रभुता कायम रखने के लिए दोनों पक्षों में कूटनीतिक सघर्ष होता रहा। फारस के तेल-विवाद, स्वेज नहर के सफ़ट, लेबनान में अमेरिकी फौजों को उतारने, ईरान की खान्ति आदि अवसरों पर दोनों ही पक्ष ताल ठोककर एक-दूसरे के विरुद्ध मैदान में उठ गए। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जो शीतयुद्ध से प्रभावित न रही हो।

1958 से 1976 तक का शीतयुद्ध

एडुश्चेव की अमेरिकी यात्रा तथा यू-2 विमान-काण्ड—1959 में शीतयुद्ध में थोड़ी कमी आई। तनाव में कमी लाने के लिए एडुश्चेव ने सितम्बर 1959 में अमेरिका की यात्रा की। आपसी मतभेदों को समाप्त करने के लिए चार बड़े देशों (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस) के शासनाध्यक्षों का एक शिखर-सम्मेलन आयोजित करना आवश्यक समझा गया पर दुर्भाग्यवश शिखर-सम्मेलन के आरम्भ में पूर्व ही 1 मई, 1960 को यू-2 विमान-काण्ड हो गया जिसने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि कर अन्तर्-शिखर-सम्मेलन को असफल बना दिया।

पेरिस शिखर-सम्मेलन—यू-2 विमानकाण्ड की घणुभ छाया मई, 1960 के शिखर-सम्मेलन पर पड़ी। जब पेरिस में शिखर-सम्मेलन शुरू हुआ तो एडुश्चेव ने यू-2 का प्रश्न उठाते हुए अमेरिकी जासूसी शायंवाही की तीव्र निन्दा की। एडुश्चेव ने माँग की कि अमेरिका को अपने जासूसी काम की निन्दा करनी चाहिए, इनके लिए माफी माँगनी चाहिए, भविष्य में ऐसे उत्तेजक कार्य बन्द करने चाहिए और हम घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए। एडुश्चेव ने शीतयुद्ध को तब पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया जब इग्नेर डिगॉल और मैकमिलन से तो हाथ मिलाया, लेकिन जब राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने हाथ बड़ाया तो एडुश्चेव ने इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं, एडुश्चेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिए गए रूसी यात्रा के निमन्त्रण को वापस ले लिया और कहा कि राष्ट्रपति महोदय को अब रूस आने की आवश्यकता नहीं है। रूसी नेता के उस रख से शिखर-सम्मेलन असफल हो गया। आइजनहॉवर के आश्वासन और डिगॉल व मैकमिलन के गतिरोध को दूर करने के प्रयत्न सम्मेलन को भग होने से न बचा सके।

कैनेडी का अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होना और ब्यूवा काण्ड—एडुश्चेव ने अपने विभिन्न भाषणों में आश्वासन दिया कि रूस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बिगाड़ने की कोई कार्यवाही नहीं करेगा। नवम्बर 1960 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने निर्वाचित में कैनेडी की सफलता के बाद शीतयुद्ध में कमी की आशा की जाने लगी। शीतयुद्ध में कुछ कमी भी आई, लेकिन 1962 में ब्यूवा के सफ़ट ने पुनः एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी।

शीतयुद्ध में शिथिलता—एडुश्चेव और कैनेडी दोनों ही नेता नि शस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति के लिए प्रयास करने लगे, अन्तः शीतयुद्ध में काफी समय तक उबाल नहीं आया। 5 अगस्त, 1963 को रूस अमेरिका और इंग्लैंड ने मास्को

में आणविक परीक्षणों पर रोक सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर किए और बाद में चीन, फ्रांस आदि कुछ राष्ट्रों के अतिरिक्त विश्व के मौ से अधिक राष्ट्रों ने सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिए। शीतयुद्ध ठण्डा पड़ गया। 1955 की आस्ट्रिया-शान्ति सन्धि के बाद पूर्व और पश्चिम का यह सबसे बड़ा समझौता था।

22 नवम्बर, 1963 को कॅनेडी की हत्या और 15 अक्टूबर, 1964 को रुश्चेव के अपदस्थ होने से सुघरते अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को एक झटका लगा। अमेरिका का नेतृत्व जानसन के हाथों में और रूस का ब्रेझ्नेव-कोसीगिन के हाथों में आया। कुछ समय तक शीतयुद्ध मन्द रहा, किन्तु जानसन की नीतियों से वियतनाम युद्ध ने तेजी पकड़ ली और उधर अरब-इजरायल संघर्ष ने भी शीतयुद्ध को पुनः तीव्रता प्रदान की।

वियतनाम युद्ध, भारत-पाक संघर्ष, अरब-इजरायल संघर्ष और शीतयुद्ध—1964 में शीतयुद्ध के लीव होने के आसार प्रकट होने लगे। रूस ने कांगो आदि में समुक्त राष्ट्रसंघ के शान्ति-स्थापना सम्बन्धी कार्यों के व्यय सम्बन्धी अपने अंश के भुगतान से इकार कर दिया। अमेरिका ने माँग की कि यदि रूस अपने अंश का भुगतान नहीं करना है तो चार्टर के उन्नीसवें अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे महासभा में मताधिकार से वंचित कर दिया जाए। इस घटना से शीतयुद्ध फिर भड़क उठा। वियतनाम-युद्ध की तीव्रता ने शीतयुद्ध को और भड़काया। उत्तरी वियतनाम की सीमाओं में घुमकर अमेरिकी वायुयान बम वर्षा करने लगे। सोवियत रूस ने इन आक्रामक कार्यवाहियों का कड़ा विरोध किया। सितम्बर, 1965 में कश्मीर के प्रश्न पर भारत-पाक संघर्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि की। पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत के विरुद्ध अपना कूटनीतिक युद्ध छिड़ने में कोई कसर नहीं रखी पर श्री शास्त्री की दृढ़ता और स्पष्टता के सामने वे सफल नहीं हो सके। जून, 1967 में अरब-इजरायल संघर्ष के समय शीतयुद्ध ने सशस्त्र संघर्ष का रूप धारण कर लिया। सोवियत रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह इजरायल को आक्रामक कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उधर अमेरिका ने इस संघर्ष के लिए सोवियत कूटनीति को दोषी ठहराया। पश्चिमी-एशिया के संकट पर दोनों गुटों में इतना वाक्ययुद्ध चला कि उनके आपस में टकराने का संकट पैदा हो गया। अरब और इजरायली नेताओं द्वारा भी जबरदस्त कूटनीतिक एवं वाक्ययुद्ध छिड़ गया और यही शीतयुद्ध अरब-इजरायल सशस्त्र युद्ध में परिणत हो गया जिसकी समाप्ति समुक्त राष्ट्रसंघीय हस्तक्षेप और अरब-राष्ट्रों की आकस्मिक पराजय में हुई। अरब-इजरायल संघर्ष के समय मुरझा-परिपक्व की अवस्था बँटक में शीतयुद्ध का दृश्य देखने को मिलता था। 18 जून, 1967 को जब महासभा में प्रश्न पर विचार होने लगा तो रूस रूसी प्रधानमंत्री ने कार्यवाही में भाग लिया। पश्चिमी गुट अभी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। सोवियत प्रधानमंत्री ने अमेरिकी प्रशासन पर बम-बम कर प्रहार किए। अरब-इजरायल संघर्ष के सन्दर्भ में इस प्रकार शीतयुद्ध आकाश धुने लगा।

ग्लासबरो का शिखर-सम्मेलन—कोमीगिन जानसन शिखर-सम्मेलन ग्लासबरो में 23 जून से 26 जून, 1967 तक चला। इसमें विद्यमान और पश्चिमी एशिया पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों नेताओं का यह शिखर-सम्मेलन चीन द्वारा हाइड्रोजन बम के परीक्षण के प्रभाव से प्रभावित था। ग्लासबरो में कोई सौदेबाजी नहीं हो सकी, लेकिन इस सम्मेलन के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में निश्चिन्त रूप से कमी आई। पश्चिमी-एशिया के संकट के सम्बन्ध में दोनों महाशक्तियों के बीच सहमति के क्षेत्र में वृद्धि हुई।

विपतनाम युद्ध में शिथिलता और शीतयुद्ध में कमी—1967-68 में विपतनाम का प्रश्न शीतयुद्ध को मँडकाता रहा। अन्त में विषय जनमत और स्वयं प्रमेरिशियों के दबाव से बाध्य होकर जानसन को उत्तरी विपतनाम पर बमबारी रोकनी पड़ी। धीरे-धीरे विपतनाम युद्ध शिथिल होना गया और शीतयुद्ध ठण्डा पड़ता गया।

मार्च, 1969 का बर्लिन-संकट और शीतयुद्ध—शीतयुद्ध में पुनः यहीं तब आई जब पश्चिमी जर्मनी ने निश्चय किया कि 5 मार्च, 1969 को फेडरल जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिमी बर्लिन में सम्पन्न किया जाय। पूर्वी जर्मन सरकार ने कहा कि पश्चिम बर्लिन अभी तक 1945 के पोड्मंडाम समझौते के अधीन है, अतः पश्चिमी बर्लिन की सरकार को इन तरह का समझौता कर देने केवल पश्चिमी जर्मनी का एक भाग मिट्टी करने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्वी जर्मनी ने आरोप लगाया कि पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव बर्लिन में कराने का निर्णय पूर्वी जर्मनी के दावे के सङ्घर्ष के लिए किया गया है। पूर्वी जर्मनी ने केवल मौखिक विरोध ही नहीं किया, बल्कि पश्चिमी बर्लिन जाने वाले मार्गों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया ताकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला निर्वाचक-मण्डल बर्लिन न पहुँच सके। किन्तु पश्चिमी जर्मनी इस बात पर तुला हुआ था कि राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिमी बर्लिन में ही किया जाए अतः वायुयानों द्वारा (हवाई मार्गान्ता प्रविबन्ध से मुक्त था) निर्वाचक-मण्डल अपने दल-बल सहित पश्चिमी बर्लिन पहुँचा। राष्ट्रपति का चुनाव-कार्य शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया। इस प्रश्न पर सोवियत संघ ने कोई बड़ा पूर्व-पश्चिम संकट खड़ा नहीं किया क्योंकि इससे कोई उद्देश्य सिद्ध होने वाला नहीं था।

मास्को-बोन समझौता, 1970 तथा शीतयुद्ध में कमी—द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही जर्मन समस्या अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेषकर महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध का प्रमुख कारण बनी हुई थी। 12 अगस्त, 1970 को मास्को ने सभी जर्मनी के बिली ग्रांट और सोवियत संघ के कोसीगिन ने एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे सुज्ञोत्तर यूरोपीय इतिहास का एक प्रयत्न-चिह्न माना जाता है। इस समझौते से शीतयुद्ध का एक प्रमुख कारण निश्चिन्त रूप से कमजोर पड़ गया। सन्धि की मुख्य बात यह थी कि दोनों पक्षों ने वस्तुस्थिति को स्वीकार करते हुए एक-दूसरे के सत्ताक शक्ति का प्रयोग न करने का फैसला किया। सन्धि से पूर्व तक

मुख्य तनाव जर्मनी के वर्तमान स्वरूप तथा युद्धोत्तर राष्ट्रीय सीमाओं के प्रश्न पर ही था, अतः जब सन्धि द्वारा वर्तमान सीमाओं को मान्यता मिल गई तो तनाव का एक मुख्य कारण समाप्त हो गया ।

बर्लिन-समझौता, 1971 तथा शीतयुद्ध का एक और कारण शिथिल— मास्को-वोन सन्धि के पश्चात् 3 सितम्बर, 1971 को अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लगभग 18 महीने की बातचीत के बाद बर्लिन-समझौते पर हस्ताक्षर हो गए । इस समझौते द्वारा पूर्वी जर्मनी में तनावपूर्ण स्थिति समाप्त हो गई । यह फैसला किया गया कि पश्चिमी बर्लिन के लोगों को पूर्वी बर्लिन तथा पूर्वी जर्मनी जाने की अनुमति प्राप्त होगी । सोवियत संघ कुछ विशेष रियायतें देने को भी तैयार हो गया ।

पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौता, 1972— 8 नवम्बर, 1972 को पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन में दोनों जर्मन-राज्यों के बीच एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें दोनों राज्यों ने एक-दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए विभिन्न मानवीय क्षेत्रों में परस्पर सहयोग का आश्वासन दिया और जर्मन समस्या के समाधान के लिए वल प्रयोग के उपायों को सदैव के लिए त्याग दिया । इस सन्धि के फलस्वरूप दोनों जर्मन राज्यों के पिछले लगभग 23 वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण सम्बन्धों की समाप्ति हो गई ।

कोरिया-समझौता, 1972 और सहयोग-वृद्धि का आयोग, 1973— उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के तनावपूर्ण सम्बन्धों ने भूतकाल में एशिया में शीतयुद्ध की चरम सीमा पर पहुँचा दिया था । 1972 में दोनों राज्यों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए । 4 जुलाई, 1972 को एक समझौता हुआ जिसमें दोनों ने वचन दिया कि वे एक-दूसरे को बमजोर करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे । दोनों राज्यों के एकीकरण की दिशा में प्रगति हुई और 1973 में दोनों के बीच पारस्परिक सहयोग-वृद्धि से लिए एक समन्वय समिति गठित की गई ।

यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जुलाई 1973— 3 से 5 जुलाई 1973 तक हेगसिटी में हुए यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को दूर कर शीतयुद्ध को समाप्त करना और यूरोप के देशों में सुरक्षा की नई भावना को जन्म देना था । सम्मेलन में रुम की ओर से यह माँग की गई कि सभी यूरोपीय देशों के लोगों को छुलकर एक-दूसरे से मिलना और विचारों का आदान-प्रदान करना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करने की कोशिश न करे । हेगसिटी-सम्मेलन ने तनाव-विन्मुखों को दम कर शीतयुद्ध के प्रभाव को कम किया ।

महान् राष्ट्रों के सम्बन्धों में परिवर्तन और तनाव-क्षेत्रों में बन्नी— 1972 के बाद से ही रुम और अमेरिका के बीच संघ नेता एक-दूसरे से मिलने लगे और चीन

मया अमेरिका में भी मेल-मिलाप बढ़ा। फलस्वरूप 1974 की समाप्ति तक शीतयुद्ध काफी ठण्डा पड़ गया।

कम्बोडियाई युद्ध की समाप्ति, अप्रैल 1975—कम्बोडिया का गृहयुद्ध शीतयुद्ध का एक बड़ा कारण बना हुआ था। 18 अप्रैल, 1975 को सिहानुक-सेनाओं (अथवा खमेर सेना) की विजय के साथ कम्बोडियाई युद्ध का अन्त हो गया और तनाव का एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र समाप्त या शिथिल हो गया।

वियतनाम युद्ध का अन्त, 30 अप्रैल 1975—1975 का वर्ष एक तरह से समूचे विश्व के लिए शुभ सिद्ध हुआ। 30 अप्रैल, 1975 को वियतनाम का ऐतिहासिक युद्ध भी समाप्त हो गया। वियतनाम युद्ध बहुत ही विस्फोटक था जिसमें कई बार महायुद्ध तक का खतरा पैदा हो गया था।

पश्चिमी एशिया शान्ति की ओर—पश्चिमी एशिया में अरब-इजरायल संघर्ष लगभग 27 वर्ष से शीतयुद्ध का कारण बना हुआ था। 1975 के मध्य में ही पश्चिमी एशिया में शान्ति के आधार अधिक प्रबल हो गए। 4 सितम्बर, 1975 को अमेरिका, मिस्र और इजरायल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसके बाद स्थिति में क्रमशः सुधार होता गया, यद्यपि अशान्ति के बरफण्डर बीच-बीच में उठते रहे। आखिर सितम्बर 1978 में अमेरिका में कैम्प डेविड में सादात-बेगिन-कार्टर शिखर वार्ता हुई और ऐसे ऐतिहासिक शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए जिसने पश्चिम एशिया में इजरायल अरब समस्या के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जून 1977—हेलसिंकी के बाद यूरोपीय सहयोग एवं सुरक्षा सम्मेलन बेलग्रेड में जून 1977 में हुआ। इस बात पर विचार किया गया कि पूर्व और पश्चिम के बीच सुरक्षा एवं सद्भाव स्थापित करने के लिए तथा यूरोपीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए। हेलसिंकी की भावना को आगे बढ़ाया गया। यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन से तनाव शैथिल्य में निश्चित रूप से मदद मिली।

1977 से मार्च 1982 के मध्य तक शीतयुद्ध के उतार-चढ़ाव

कार्टर प्रशासन और शीतयुद्ध—20 जनवरी, 1977 को जिम्मी कार्टर संप्रुक्त-राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कार्टर ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और तनाव शैथिल्य को बढ़ावा मिला। पहले उन्होंने वियतनाम के युद्ध में जबरन लाभबन्दी का विरोध करने वालों को क्षमादान सम्बन्धी आदेश प्रसारित किया। उपराष्ट्रपति वाल्टर माडेल ने अनेक देशों की सद्भावना यात्रा की। कार्टर प्रशासन ने पश्चिम एशिया की समस्या के निदान के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। कार्टर ने अमेरिका में कैम्प डेविड में सितम्बर 1978 में सादात बेगिन-कार्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। विश्व राजनय में शायद यह पहला अवसर था जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी प्रतिष्ठा को दाब पर रख कर

बिसी मसले को सुलझाने में व्यक्तिगत दिलचस्पी ली हो। 26 मार्च, 1979 को कार्टर की उपस्थिति में वाशिंगटन-सादात और बेगिन के हस्ताक्षरों के साथ मिस्र और इजरायल में एक शान्ति-सन्धि सम्पन्न हुई। वियतनाम के प्रति भी अमेरिका का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक बना। समुक्त राष्ट्रसंघ में वियतनाम के प्रवेश को रोकने की अमेरिका ने कोई कोशिश नहीं की।

कार्टर प्रशासन ने अपने कुछ कदमों से जहाँ एक ओर तनाव-शैथिल्य को कम किया वहाँ दूसरी ओर इसे उभारा भी। 1979 के मध्य क्यूबा में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति को लेकर अमेरिका तथा क्यूबा के बीच गम्भीर तनाव उत्पन्न हो गई। कार्टर ने कैरेबियन में 'टास्क फोर्स' (अग्रिम सेना) तैनात करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कुछ नए 'रक्षा उपायों' की भी घोषणा की। यह भी कहा गया कि अमेरिका क्यूबा में सोवियत सैनिकों की ठीक सख्या ज्ञात करने के लिए अपनी उपग्रह व्यवस्था को पुनर्गठित करेगा। अमेरिका ने यह घोषणा भी कर दी कि क्यूबा में तैनात सोवियत सैनिकों से आक्रमण के खतरे की स्थिति में यदि किसी देश ने उससे सहायता माँगी तो उसे तुरन्त सहायता पहुँचाई जाएगी तथा पश्चिमी पनोरिडा के मुख्य सैनिक प्रधान कार्यालय में पूर्णकालिक एक कैरेबियाई समुक्त सैनिक टुकड़ी तैनात की जाएगी जो इस क्षेत्र के किसी भी भाग पर रूसी आक्रमण का खतरा होने पर सक्रिय हो जाएगी। अमेरिका की इस प्रकार की घोषणाओं से शीतयुद्ध को बढ़ावा मिला और सकट ने गम्भीर रूप धारण कर लिया। सोवियत संघ ने अमेरिका को चेतावनी दे दी कि क्यूबा में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति को अनावश्यक तूल देकर राष्ट्रपति कार्टर आग से खेलने का खतरा मोल न लें। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका की घोषणा के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई और स्वयं अमेरिका में भी कार्टर की नीति का भारी विरोध होने लगा। इस पर कार्टर को नम्र एवं अपनाता पड़ा और उन्होंने यह कहकर सकट टालने की कोशिश की कि हम और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति दोनों देशों की सुरक्षा के लिए भारी खतरा है और क्यूबा में 2-3 हजार रूसी सैनिकों की उपस्थिति अमेरिकन सुरक्षा को कोई चुनौती नहीं हो सकती। कार्टर ने यह भी कहा कि इस 'नाइट-2' समझौते को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और मनभेद है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु-युद्ध की आशंकाओं को दूर करने के अपने प्रयत्नों को निर्लज्जि दे दें। कार्टर के इस प्रकार के वक्तव्य के बाद क्यूबा की विस्फोटक स्थिति शान्ति हो गई, लेकिन शीतयुद्ध का वातावरण गर्म अवश्य हो गया। भारत उप-महादीप में भी कार्टर प्रशासन ने तनाव-शैथिल्य के वातावरण को घाघान पहुँचाया। पाकिस्तान और चीन को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उबलावा देने की नीति से इस क्षेत्र में तनाव का वातावरण बढ़ा। कार्टर प्रशासन ने भारत के साथ किए गए पुर्नाने समझौते पर ध्यान न करके भी भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में तनाव पैदा किया।

अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप : शीतयुद्ध में श्रुति—दिसम्बर 1979 में अफगानिस्तान में हुई तीवरी शक्ति के फलस्वरूप राष्ट्रपति घमोन का नरका पतन

गया और बबरक करमात नए राष्ट्रपति बने। नई सरकार के आमन्त्रण पर, अफगान नान्ति की रक्षा के लिए, अफगानिस्तान ने सोवियत सैनिक हस्तक्षेप शुरू हो गया, जिससे उस क्षेत्र में और साथ ही महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध की स्थिति को बढ़ावा मिला है। ईरान ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को ईरानी सरकार द्वारा बन्धक बना लिए जाने और उन्हें छुड़ाने के सारे प्रयत्नों के असफल हो जाने से अमेरिका पहले से ही काफी अपमानित हो चुका था और अब अफगानिस्तान में सोवियत सेना के पहुँच जाने पर स्वाभाविक था कि अमेरिका बौखला जाता। अतः अमेरिका ने अफगानिस्तान की घटना को तिल का ताड़ बनाना शुरू कर दिया और फलस्वरूप शीतयुद्ध ने एक बार फिर उग्र रूप धारण कर लिया। अमेरिका ने, सोवियत सतरे की आशका पैदा कर अफगानिस्तान को 20 करोड़ डॉलर के हथियार देने की घोषणा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री हैरल्ड ब्राउन को पीकिंग भेजा गया ताकि चीनी नेताओं से मिलकर सोवियत विस्तार को रोकने की योजना बनाई जा सके। राष्ट्रपति कार्टर ने अमेरिकी कांग्रेस में सॉल्ट-द्वितीय पर बहस रुकवा दी और सोवियत सघ को घनाज देने एवं आधुनिक प्राविधि की जानकारी देने के अपने पूर्व फैसले को बदल दिया। यही नहीं, कार्टर ने मास्को में होने वाले ओलम्पिक खेलों के बहिष्कार की घमस्ती दी तथा आगे चल कर बहिष्कार भी किया। उन्होंने अपने पश्चिम यूरोपीय मित्र राज्यों से भी अनुरोध किया कि वे सोवियत सघ के साथ अब कोई सहयोग न करें। सुरक्षा परिषद् को घँठक बुलाकर सोवियत कार्यवाही की निन्दा का प्रयत्न किया गया। अमेरिकी कदमों से शीतयुद्ध को काफी बढ़ावा मिला। अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान में सोवियत उपलब्धि को नाकामयाब करने का असफल प्रयत्न किया। आखिर धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी, क्योंकि कनाडा और ब्रिटेन को छोड़कर अन्य पाश्चात्य देशों ने अमेरिका का पूरा समर्थन नहीं किया और पाकिस्तान तथा चीन का उत्साह भी समय के साथ ठण्डा पड़ गया। अप्रैल 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के रहने पर जब सोवियत सघ और अफगानिस्तान के नेताओं में एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए तो यह तथ्य पुनः पुष्ट हो गया कि सोवियत सैनिकों को अफगान सरकार ने बुलाया है और अपने यहाँ अपनी रक्षा के लिए रखा है, रूप ने चलाकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मार्च 1982 के मध्य तक अफगानिस्तान के प्रश्न पर शीतयुद्ध काफी स्थिर पड़ा हुआ है, यद्यपि अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र अफगानिस्तान ने सोवियत सैनिकों की वापसी की माँग का रुख अपनाए हुए हैं और नवम्बर 1981 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी सोवियत सघ से अफगानिस्तान से हटने का अनुरोध किया था।

ईरान-ईराक संघर्ष—ईरान और ईराक के बीच तनातनी काफी असें से चल रही थी जिसने सितम्बर 1980 को भयावह युद्ध का रूप ले लिया। इन दोनों अरब देशों के युद्ध के फलस्वरूप शीतयुद्ध को बढ़ावा मिला और खाड़ी क्षेत्र में महाशक्तियों के दखल का खनरा भी पैदा हो गया। यद्यपि दोनों देश अभी भी एक दूसरे के प्रति

शान्तापूर्ण रूप अपनाए हुए हैं तथापि युद्ध के बादल लगभग छोट गए हैं और इस दृष्टि से शीतयुद्ध मार्च 1982 के अन्त में काफी ठण्डा पड़ चुका है।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र-सप्लाई—जनवरी 1981 में पदाहुद होने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने पाकिस्तान को शस्त्रों से सज्जित करने की नीति अपनाई है और प्राधुनिकतम एफ-16 विमान देने का निर्यात करके भारतीय उपमहाद्वीप की शान्ति को खतरा पैदा किया है तथा भारत-पाक के बीच तनाव-क्षेत्र का विस्तार किया है। रीगन की अन्तर्राष्ट्रीय नीतियाँ कुल मिलाकर तनाव बढ़ाने वाली सिद्ध हुई है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस शीतयुद्ध का विकास हुआ वह भारी उतार-चढ़ाव के उपरान्त 1975 के मध्य से ही शिथिल पड़ता गया है। यद्यपि समय-समय पर विभिन्न कारणों से शीतयुद्ध की प्रोत्साहन मिलता रहा है फिर भी महाशक्तियों के स्वयं के कारण वह कभी विस्फोटक नहीं बन सका है। विश्व-शान्ति की दिशा में यह एक शुभ संकेत है। जिस तरह अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बनता जा रहा है और तनाव तथा सघर्ष क्षेत्रों को सीमित रखने की जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं उसमें यही आशा बलवती होनी है कि शीतयुद्ध का विस्फोट पहले की भाँति नहीं हो सकेगा। भोके-वेमोके शीतयुद्ध उभर सकता है लेकिन उसकी तीव्रता पहले जैसी नहीं होगी और वह सामयिक तेजी दिखाकर पुनः शान्त हो जाएगा।

शीतयुद्ध की शिथिलता के कारण

शीतयुद्ध के इतिहास के इस विवेचन से स्पष्ट है कि काफी उतार-चढ़ाव के बाद पिछले वर्षों से शीतयुद्ध की उग्रता निरन्तर घटती गई है। इसके मूल में जो मुख्य कारण रहे वे ये हैं—

1. दोनों महाशक्तियाँ यह अनुभव करती जा रही हैं कि सैनिक शक्ति के दल पर समस्या का निदान बहुत कठिन और व्यय-साध्य है। विपत्तनाम-युद्ध ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के घुटने टिका दिए, युद्ध से उसके सैनिकों का ही विनाश नहीं हुआ बल्कि उसका अर्थ-तन्त्र भी सड़क में पड़ गया, उसका व्यापार-पन्तुलन बिगड़ गया और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाजार में डॉलर की भाव तक खतरे में पड़ गई।

2. दोनों महाशक्तियों को यह आशंका भी सताने लगी है कि शीतयुद्ध कभी भी ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे तृतीय महायुद्ध का विस्फोट हो जाए। क्यूबा के महान् सफट के बाद से ही महाशक्तियों की यह नीति स्पष्ट दिखाई देने लगी है कि वे परस्पर टकराने जैसी किसी भी स्थिति में बचती हैं।

3. पूँजीवादी और साम्यवादी शिविरों में अर्थ मंडलान्तिव सघर्ष उतना तीव्र नहीं रहा है जितना पहले था। अमेरिका के मित्रराष्ट्र शीतयुद्ध की राजनीति से पृथक् रहकर साम्यवादी देशों से व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने लगे हैं और अमेरिका भी अर्थ दम क्षेत्र में उतर आया है। पूँजीवादी गुट ने साम्यवादी देशों के साथ बड़े

पैमाने पर व्यापार करने का रास्ता खुला रखने के लिए यह उपयुक्त समझा है कि शीतयुद्ध को यथासाध्य बढ़ावा न दिया जाए।

4. गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और गुट-निरपेक्षता की नीति ने शीतयुद्ध की उग्रता कम करने में महती भूमिका निभायी है।

5. संयुक्त राष्ट्रसंघ में अब महाशक्तियों का प्रभाव वंसा नहीं रहा है जैसा पहले था। अफ्रीकियायी राष्ट्रों की संख्या बढ़ गई है और 'तृतीय विश्व' की आवाज को अब पहले की तरह बढ़ावा जाना आसान नहीं है। इस स्थिति ने शीतयुद्ध की उग्रता को कम किया है।

6. सोवियत संघ द्वारा स्थापितबादी उग्र नीति का परित्याग कर निरन्तर सह-प्रस्थित्व की नीति पर बल देने से शीतयुद्ध का की शिथिल हुआ है। अमेरिकी नेतृत्व ने भी सोवियत मंत्री और सोवियत नीति के महत्त्व को समझकर सहयोगी रख अपनाया है। दोनों ही पक्षों में इस विचारधारा ने बल पकड़ा है कि परस्पर मनभेद होने के बावजूद दोनों के सम्बन्ध शान्तिपूर्ण रह सकते हैं।

7. पिछले कुछ वर्षों से बड़े राष्ट्रों के नेताओं से सम्पर्क बढ़ा है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सोवियत रुम और चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनकी पहल से एक ओर रूस तथा अमेरिका और दूसरी ओर चीन तथा अमेरिका के जो शिखर सम्मेलन हुए उनसे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के मुधरने में काफी सहयोग मिला है।

8. शीतयुद्ध की उग्रता कम करने में भारत की भूमिका भी विशेष महत्त्वपूर्ण रही है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत गुट-निरपेक्षता की नीति पर दृढ़ रहा है जिससे विभिन्न देशों में तनावों के कम होने में सहायता मिली है।

9. मास्को-चीन समझौता, बर्लिन-समझौता, पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच समझौता, कोरिया-समझौता, कम्बोडियायी और वियतनामी युद्ध की समाप्ति, आदि घटनाओं ने यह आजा उत्पन्न कर दी है कि विश्व शीतयुद्ध के भँवर से निकल चुका है और शान्ति तथा सह-प्रस्थित्व की शक्तियाँ बलवती हो रही हैं।

वास्तव में महान् राष्ट्रों के सम्बन्धों में पिछले वर्षों में जो आग्निकारी परिवर्तन हुए हैं, उन्हीं के फलस्वरूप अनेक समस्याओं का निदान हो सका है और तनाव के क्षेत्र समाप्त तथा कम हुए हैं। विश्व का बलवाण दमी में है कि महाशक्तियाँ दूसरे देशों में हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दें, घापसी सम्बन्धों को मधुर बनाएँ और प्रत्येक समस्या का समाधान शस्त्र-बल की जगह पारस्परिक वार्ता द्वारा करें।

शीतयुद्ध और देतांत (Cold War and Detente)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों के अनुसार देतांत¹ अथवा सोवियत-

1 'देतांत' एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है—पनाय शैथिल्य, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में इसका अर्थ है सम्-जर्मनिया तनाव में बन्ती और उसमें बरफी हूँ मिलाया गया सहयोग की भावनाओं से जमाया जाता है।

अमेरिका मंत्री एव सहयोग का प्रारम्भ केंनेडी-खुश्चेव के समय से हुआ। सत्ता से उनके अकस्मात् हटने के कारण कुछ समय तक मंत्री और सहयोग का मार्ग अवलम्बित हो गया, किन्तु निम्नन और ब्रेझ्नेव ने सहयोग के सूत्रों का पुनः विकसित किया जिनमें अमेरिका के विदेश-सचिव डॉ. होमिजर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही और निम्नन के चल जाने के बाद फोर्ड तथा कार्टर के समय भी रुम के साथ सामान्यीकरण की प्रक्रिया चलती रही यद्यपि दोनों महाशक्तियों के बीच मंत्री और सहयोग के विकास की गति उतनी तीव्र नहीं रही जितनी निम्नन के समय थी। रीगन प्रशासन के दौरान कुछ तनाव पुनः उत्पन्न हुआ।

द्वैतता (मोबियन-अमेरिकी मंत्री एव सहयोग) के प्रारम्भ के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं—

प्रथम, अणुबल के रहस्य पर अमेरिका का एकाधिकार समाप्त हो जाने के कारण रुम और अमेरिका के बीच अस्त्र-शस्त्र की दृष्टि से एक समतुल्य-मा पैदा हो गया है। इसके फलस्वरूप भूतपूर्व अमेरिकी विदेश सचिव डलैम की वह नीति उपयोगी नहीं रही जिसमें साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सशस्त्र-संघर्ष की बात पर बल दिया जाता था। वॉलिन की घेराबन्दी, कोरिया का युद्ध, क्यूबा-वाण्ड आदि ने स्पष्ट कर दिया कि महाशक्तियों के बीच 'सहयोग' की आवश्यकता है, 'टकराहट' की नहीं।

द्वितीय, रुम की आर्थिक आवश्यकताओं ने उसे अमेरिका की मंत्री अग्नि करने के लिए प्रेरित किया। साम्यवादी क्रान्ति के पाँच दशक बाद भी मोबियन जनता उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही थी जिनसे वे उच्च जीवन-स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो। अमेरिका के पास यह उत्तम तकनीकी ज्ञान था लेकिन रुम इसका भागीदार तभी बन सकती थी जब वह अमेरिका के प्रति संघर्ष के बजाए सह-अस्तित्व की नीति अपनाता। अन्तः-स्ट्रानिनांतर युग में मोबियन नेताओं ने पूँजीवाद के साथ सह-अस्तित्व के विज्ञान का प्रतिपादन किया और इस तरह दोनों महाशक्तियों में सहयोग का द्वार खुल गया।

तृतीय, साम्यवादी चीन के साथ संघर्ष उत्पन्न होने के कारण मोबियन संघ के लिए आवश्यक हो गया कि वह चीन के समक्ष अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए पश्चिमी देशों और मुख्यतः अमेरिका से शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करे।

चतुर्थ, भारत की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। एक ओर तो रुम ने समझ लिया कि चीन के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने में भारत की भूमिका बहुमूल्य है और दूसरी ओर अमेरिका तथा उसके साथी राष्ट्रों ने समझ लिया कि रुम-भारत मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर प्रभावशाली गुन खिला सकती है। भारत की इस केन्द्रीय स्थिति के कारण महाशक्तियों में वास्तविक सहयोग को प्रोत्साहन मिला। भारतीय नेताओं ने सर्वेसर्व्व बात का प्रयत्न किया कि भीतमुद्ध के कारण समाप्त हो और विश्व के बड़े राष्ट्रों के बीच सहयोग का वातावरण बने।

पंचम, अमेरिका विपतनामी युद्ध से थक चुका था। वह विपतनामी युद्ध के पलटल से सम्मानपूर्वक तभी निकल सकता था जब सोवियत सघ का सहयोग प्राप्त हो।

उपर्युक्त कारणों से यह स्वाभाविक था कि दोनों महाशक्तियाँ परस्पर तनाव और सघर्ष का मार्ग छोड़कर मैत्री सहयोग का मार्ग अपनाती।

देतांत का शीतयुद्ध पर प्रभाव

देतांत अर्थात् रूस-अमेरिकी सहयोग का शीतयुद्ध पर निर्णायक प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था। दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव ही शीतयुद्ध की जड़ था और जब दोनों महाशक्तियों ने यह नीति अपना ली कि वे क्रमशः सहयोग के मार्ग पर अग्रसर होने लगे शीतयुद्ध भी ठण्डा पड़ने लगा और कुल मिलाकर यह प्रक्रिया अभी जारी है।

सैद्धान्तिक संघर्ष बनाम शक्ति-राजनीति (Ideological Conflict Vs Power Politics)

अब हमें 'शीतयुद्ध' के एक दूसरे पहलू पर भी कुछ विचार करना चाहिए। प्रायः यह कहा जाता है कि 'शीतयुद्ध' एक सैद्धान्तिक संघर्ष (Ideological Conflict) है जिसमें दो विरोधी जीवन-पद्धतियाँ (उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वोपकारवादी साम्यवाद) सर्वोच्चता के लिए सघर्षरत हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि शक्ति-राजनीति के इस युग में सोवियत सघ और संयुक्तराज्य अमेरिका के बीच जो एक विशेष प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता है, वह बहुत कुछ सैद्धान्तिक है। इसके पीछे एक गहन सामाजिक दर्शन है जो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का एक मुख्य कारण बन गया है। संयुक्तराज्य अमेरिका सोवियत प्रणाली को एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्युत्पन्न मानता है जिसका उद्देश्य अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर अथवा अपना प्रभाव डालकर साम्यवाद का प्रसार करना है। दूसरी ओर सोवियत सघ पश्चिमी देशों की प्रणालियों का शोषण, आश्रमणहीन उपायों द्वारा स्वार्थ-लाभ तथा सगठित लूट-लूटोड पर आधारित मानता है। दोनों देशों और उनके पिछले गुरु राष्ट्रों के दृष्टिकोण परस्पर इस तरह विरोधी हैं कि उनका प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ा है और मंत्र व हम व अमेरिका का वैचारिक सघर्ष प्रवेश कर गया है। यह वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक संघर्ष आज विश्व-राजनीति का एक आधार बन चुका है और इसी सघर्ष को जारी रखने एवं दृढ़ता से सफलता प्राप्त करने के प्रत्येक सम्भव उपाय सोचे जा रहे हैं।

बैसे तो इस सैद्धान्तिक संघर्ष का उद्भव प्रधानतः सन् 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद ही हो गया था, किन्तु द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में इसने बिनाशजनक और भीषण रूप धारण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव में वृद्धि होती गई और विश्व की समस्याओं के प्रति विरोधी नीतियाँ परस्पर टकराने लगीं। साम्यवाद को सीमित रखने के लिए अमेरिका ने विभिन्न बड़म उदाए। ट्रूमैन सिद्धान्त का प्रतिपादन मार्शल-योजना जैसे कार्यक्रमों की पूर्ति, मैक

एक प्रादेशिक संगठनों की स्थापना आदि बातों से यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका ने साम्यवाद के विरुद्ध कमर कस ली है। दूसरी ओर साम्यवाद ने पूंजीवादी घेरो को तोड़कर साम्यवाद के प्रसार का सकल्प ले लिया। इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि द्वितीय महायुद्ध के बाद 'शीतयुद्ध' का दानव समग्र संसार को घसने लगा। स्थिति यह बन गई कि सैद्धान्तिक सघर्ष में विजय पाने और शीतयुद्ध के कायम रखने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सैनिक सभी प्रकार के उपाय काम में लाए जाने लगे लेकिन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ ऐसे भी कार्य हो रहे हैं जिनमें सचमुच विरोधाभास है। संयुक्तराज्य अमेरिका लोकतन्त्र की साम्यवाद से रक्षा के नाम पर विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता देता है ताकि वहाँ की स्थिति मुद्दूढ़ रहे और साम्यवाद के प्रसार का अवसर न मिले। लेकिन यह आर्थिक सहायता उन्हीं देशों को प्राप्त होती है जो सोवियत संघ के विरोधी हैं या उनको जिनकी स्थिति अब अच्छी नहीं है और जहाँ लोकतन्त्र के प्रति आस्था मिटती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। उदारवाद को महत्व न दिया जाकर विचारों की विभिन्नता को घृणा से देखा जाता है। स्वतन्त्र विचारों के लिए आदर न होने से विश्व में अविश्वास की राजनीति को बल मिला है।

दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति इतने संशुभ हैं कि अपनी व्यवस्था के रक्षार्थ उन्होंने गुप्तचरों का एक विश्व-व्यापी जाल बिछा रखा है। सैद्धान्तिक सघर्ष में और एक-दूसरे के दर्शन से अपने दर्शन को अथवा अपने रहन-सहन को श्रेष्ठतर सिद्ध करने के लिए प्रचार के सभी साधन अपनाए जाने हैं। प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देकर अविश्वसित देशों की मित्रता खरीदी जाती है, सामरिक सामग्री पर नियन्त्रण किया जाता है और दुर्बल देशों के अस्तित्व को नियन्त्रित किया जाता है। इतना ही नहीं, अन्य देशों में जो राजसत्ता के लिए सघर्ष होते हैं उनमें किसी दल विशेष का पक्ष लेकर सैद्धान्तिक सघर्ष को बढ़ाया जाता है।

इस तरह वर्तमान शीतयुद्ध का एक सर्वोपरि आधार सैद्धान्तिक या वैचारिक सघर्ष (Ideological Conflict) ही है। आर्नोल्ड टॉयनबी ने शीतयुद्ध को एक सैद्धान्तिक सघर्ष मानते हुए विश्व-राजनीति की 'द्वि-ध्रुवी' व्याख्या की है। टॉयनबी के अनुसार वर्तमान समय में विश्व-राजनीति में केवल दो सिद्धान्त और केवल दो शक्तियाँ हैं—उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद और संयुक्तराज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस। यह कहा जाना है कि संसार के अन्य राज्यों के पास उसके अनिश्चित और कोई अन्य विकल्प नहीं है कि इन दो महाशक्तियों में से एक-न-एक का साथ दें। मार्शल टीटो का सोवियत संघ के विरुद्ध विद्रोह अथवा भारत का असंतोषनावाद किसी भी ऐच्छिक विकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं करते, प्रतिष्ठित महाशक्तियों द्वारा चयनित विकल्प (Choice Allowed) का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात इसी में स्पष्ट है कि यदि रूस और अमेरिका में कभी अन्तिम सघर्ष का अवसर उपस्थित हो जाए तो यूगोस्लाविया अथवा भारत के पास निश्चय इनके कोई प्रभावी विकल्प नहीं रहेगा कि वे दोनों में से किसी एक पक्ष का साथ दें।

यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि स्वयं पश्चिमी शक्तियाँ और साम्यवादी देश भी शीतयुद्ध के एक सैद्धान्तिक सघर्ष होने का दावा करते हैं। पश्चिमी शक्तियों द्वारा इसे एक सैद्धान्तिक सघर्ष मानने का स्पष्टतम प्रमाण 5 मार्च, 1946 की चर्चित की विद्वात 'फुल्टन वक्तृता' है जिसमें उन्होंने यूरोप के आर-पार सोवियत 'लोह घाबरण' (Iron Curtain) की निन्दा करते हुए सोवियत सन्देश में ईसाई सभ्यता की रक्षा करने तथा साम्यवादी निरकुशता द्वारा गुलाम बनाए गए लोगों को स्वतन्त्र कराने के लिए एक एंग्लो-अमेरिकी मंत्री सन्धि पर बल दिया था। शीतयुद्ध एक सैद्धान्तिक सघर्ष है, इस सम्बन्ध में रूसी दावे की पुष्टि उक्त घोषणा-पत्र ने निम्नलिखित शब्दों द्वारा की जा सकती है जो 5 अक्टूबर, 1947 को रुम सहित 18 प्रमुख साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मास्को तथा वारसा में एक साथ प्रसारित किया गया था—

“.....ये विरोधी राजनीतिक विचारधाराएँ उजगार हो गई हैं। एक ओर सोवियत संघ तथा अन्य लोकतन्त्रीय राज्यों का उद्देश्य साम्राज्यवाद का विनाश करना तथा लोकतन्त्र की मजबूत बनाना है। दूसरी ओर इंग्लैंड तथा अमेरिका का उद्देश्य साम्राज्यवाद को मजबूत बनाना तथा लोकतन्त्र का गला घोटना है। चूंकि सोवियत संघ तथा लोकतान्त्रिक देश विश्व-प्रमुख एवं लोकतन्त्रीय आन्दोलनों के दमन की साम्राज्यवादी आकांक्षओं की पूर्ति में बाधक हैं, इसलिए इंग्लैंड तथा अमेरिका के खूनी साम्राज्यवादियों ने सोवियत संघ तथा नए लोकतन्त्र के प्रतीक अन्य देशों के विरुद्ध एक अभियान प्रारम्भ कर दिया है।.... इन परिस्थितियों में साम्राज्यवाद-विरोधी लोकतन्त्रीय समुदाय के लिए नगठन होना तथा साम्राज्यवादी समुदाय की प्रमुख शक्तियों के विरुद्ध अपनी नीति निश्चित करने हेतु एक सामान्य मञ्च (Common Platform) का निर्माण करना आवश्यक है।

निष्कर्ष यही निकलता है कि शीतयुद्ध को एक सैद्धान्तिक सघर्ष की नज़ा दिया जाना गलत नहीं है, पर यह कहना अवश्य भ्रामक है कि यह केवल एक सैद्धान्तिक सघर्ष है। शीतयुद्ध और सैद्धान्तिक सघर्ष पर्यायवाची नहीं है बल्कि सैद्धान्तिक सघर्ष शीतयुद्ध के एक प्रधान कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। नेतृत्व की होड़, प्रभाव-विस्तार की होड़, शक्ति-प्रतियुद्धा, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समस्याएँ आदि अनेक अन्य तत्त्व भी हैं जो शीतयुद्ध भड़काने हैं।



पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण तथा पुनरगठन

(RE-BUILDING AND RE-ORGANISATION
OF WESTERN EUROPE)

“अब राजनीतिक शक्ति एवं नेतृत्व में केन्द्रीय तथा पश्चिमी यूरोप का एकाधिकार नहीं रहा है।”
—हैराल्ड एवं स्पाउड

7 मई, 1945 को जर्मनी के साथ विराम-सन्धि होने के पश्चात् 2 सितम्बर, 1945 को जापान के प्रतिनिधियों और जनरल मैकार्थर के मध्य विधिवत् विराम-सन्धि सम्पन्न हो जाने पर द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति हो गई। जर्मनी और जापान के आत्मसमर्पण से सैनिक संघर्ष का अन्त अवश्य हो गया, लेकिन अन्य विवट समस्याओं का समाधान अभी बाकी था—(1) पराजित शक्तियों के साथ शान्ति-सन्धियाँ कर वांछित व्यवस्था स्थापित करना, एवं (2) आर्थिक दृष्टि से घटस्त यूरोप का पुनर्निर्माण करना। दूसरे शब्दों में महायुद्ध के उपरान्त सबसे गम्भीर समस्या ‘यूरोप के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन’ की थी। द्वितीय महायुद्ध ने विश्व-इतिहास के निर्माता यूरोप का आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से पचाहिज तथा ‘तमस्या प्रधान’ (Problem Europe) बना दिया था। जर्मनी और इटली नष्ट हो गए थे तथा उनके साम्राज्य इतिहास की कहानी बन चुके थे। ब्रिटेन और फ्राँस तीसरी श्रेणी के राष्ट्र बन गए थे। आर्थिक दृष्टि से यूरोप के विजेता राष्ट्रों की भी दशा इतनी भोचनीय बन चुकी थी कि उनकी स्थिति पराजित राष्ट्रों में कोई विशेष अच्ची नहीं थी। 1939 में ब्रिटेन विश्व का एक प्रमुख ऋणदाता राष्ट्र था, लेकिन 1945 में वह स्वयं एक ऋणी राष्ट्र हो गया और उसकी विदेश देनदारियाँ बहुत बढ़ गईं। महायुद्ध के बाद वास्तव में केवल दो ही महाशक्तियाँ रह गईं—सोवियत रुस तथा मयुक्तराज्य अमेरिका।

अमेरिका के लिए महायुद्ध प्रच्यन्न रूप में एक वरदान सिद्ध हुआ। प्रथम महायुद्ध ने अमेरिका को एक ऋणी में ऋणदाता राष्ट्र का रूप दिया था और द्वितीय महायुद्ध के बाद सम्पूर्ण मगार पर उसका आर्थिक प्रभुत्व छा गया। उसकी

राजनीतिक-आर्थिक-सैनिक समृद्धि का रहस्य यही था कि अन्य सघर्षरत राष्ट्रों के समान उसे युद्ध-जनित विनाश का सामना नहीं करना पड़ा था। न तो उसकी भूमि पर युद्ध लड़ा गया था और न ही उसे शत्रु की क्रूर बमबर्षा का शिकार होना पड़ा था। अतः यूरोप के शंर-साम्यवादी राष्ट्रों का अपने पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका का मुँह ताकना और उसका नेतृत्व स्वीकार करना स्वाभाविक था। अमेरिका को चुनौती दी तो केवल छोड़ियत एम ने जो द्वितीय महायुद्ध के घोर विनाश के बावजूद एक महाशक्ति के रूप में उभरा था और पूर्वी यूरोप को 'नाल' बना चुका था तथा बताता जा रहा था। युद्धोपरान्त 1948 तक की तीन वर्ष की अल्पावधि में ही स्टालिन ने पूर्वी यूरोप के 7 देशों को पूरी तरह लाल बनाकर, स्वतन्त्र बिन्दु के सामने जबरदस्त राजनीतिक और वैचारिक चुनौती प्रस्तुत कर दी थी। साम्यवाद के प्रसार को आशंका से भयभीत अमेरिका यूरोप के पुनर्निर्माण की दिशा में जुट गया।

पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन का वर्णन कमज. निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है —

- (1) शान्ति-निर्माण की समस्या (Problem of Peace-making)
- (2) आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण (Economic Recovery and Integration)
- (3) पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा (Military Security of Western Europe)

शान्ति-निर्माण की समस्या (Problem of Peace-making)

युद्धोत्तर शान्ति-स्थापना का कार्य प्रथम महायुद्ध के उपरान्त के शान्ति-स्थापना के कार्य से कहीं अधिक सरल प्रतीत होता था, क्योंकि विजेता राष्ट्र महायुद्ध काल में ही विविध सम्मेलनों और बार्ताओं द्वारा शान्ति स्थापना के मार्ग की काफी दूरी तय कर चुके थे, परन्तु यह आशा कलीभूत नहीं हुई। द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद तक भी शान्ति-सन्धियों के प्राप्ति तैयार नहीं हो सके। 10 फरवरी, 1947 तक केवल इटली, रूमानिया, बल्गेरिया, हंगरी और फिनलैण्ड के साथ शान्ति-सन्धियाँ सम्पन्न हो सकीं। जापान के साथ तो युद्ध-समाप्ति के लगभग साढ़े छ वर्ष बाद 28 अप्रैल, 1951 को शान्ति-सन्धि की गई, और यह भी एक अग्रणी शान्ति-सन्धि ही थी क्योंकि इस ने इससे इन्कार कर दिया। रूस और जापान के मध्य युद्ध की औपचारिक समाप्ति तो अक्तूबर, 1956 में हुई जब दोनों राष्ट्रों द्वारा एक संयुक्त विज्ञापित जारी की गई। ऑस्ट्रिया के साथ शान्ति-सन्धि युद्ध समाप्ति के लगभग 10 वर्ष बाद 27 जुलाई, 1955 को कार्यान्वित की गई और जर्मनी के एकीकरण की समस्या आज भी जीवन्त है यद्यपि व्यवहार में दो जर्मनियों का अस्तित्व स्वीकार करते हुए दोनों को संयुक्त राष्ट्रसंघ में अलग-अलग सदस्यता प्रदान की जा चुकी है।

शान्ति-निर्माण में कठिनाइयाँ और प्रारम्भिक कार्य

महायुद्ध के उपरान्त शान्ति-व्यवस्था का कार्य प्रत्यधिक कठिन और दुष्कर मिष्ट हुआ जिसके मूल में कुछ प्रमुख कारण थे—(1) विजेता-राष्ट्रों के पारस्परिक मतभेदों और अविश्वासों ने उग्र रूप धारण कर लिया तथा शीतयुद्ध शुरू हो गया, (2) रूस और अमेरिका दोनों में ही प्रभुत्व-विस्तार की प्रतिस्पर्धा छिड़ गई और यह प्रश्न गंभीर हो गया कि पराजित देशों की यथाशीघ्र आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए, (3) शान्ति व्यवस्था के लिए विदेश मन्त्रियों की जो परिपक्व योजनाई गई उसमें 'सर्वसम्मति से निर्णय' का निश्चय किया गया जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि इसके द्वारा दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के कार्यों पर 'निषेधाधिकार' प्राप्त हो गया जिससे वे किसी भी निर्णय को रोकने की स्थिति में आ गए, (4) मित्रराष्ट्रों के विदेश मन्त्री उतने अनुभवी और चतुर नहीं थे जितने रूसी विदेश मन्त्री और वे स्वयं पारस्परिक मतभेद के भी शिकार थे, एक (5) विदेश मन्त्री-परिपक्व में फ्रांस और चीन के विदेश मन्त्रियों को भी सम्मिलित कर लिया गया जबकि सन्धियों का प्रारूप तैयार करने और निर्णय करने के कार्य में वे भाग नहीं ले सकते थे। बाद में इस समस्या को सुलझा लिया गया, तो भी यह व्यवस्था बनी रही कि वे निर्णय के समय मतदान में भाग नहीं ले सकते।

इन सभी कारणों से और पारस्परिक अविश्वास एक शयुता के वातावरण के कारण शान्ति-समझौते के प्रयत्नों का वही हाल हुआ जो एक ऐसी गाड़ी का होता है जिसके दोनों ओर घोड़े जुते हुए हो किन्तु ये घोड़े उस गाड़ी को विपरीत दिशा में खींच रहे हों और उनमें से अधिक शक्तिशाली घोड़ा गाड़ी को बहुत धीरे-धीरे आगे की दिशा में खींच सका हो।

शान्ति-स्थापना के प्रयास में विदेश मन्त्रियों की परिपक्व की पहली बैठक लन्दन में सितम्बर-प्रकृतवर्, 1945 में हुई। बाद में इटली, रूमानिया, बल्गेरिया, हंगरी और फिनलैंड आदि देशों से सन्धि के लिए दिसम्बर, 1947 तक इस परिपक्व के विभिन्न सम्मेलन पेरिस, न्यूयॉर्क, मास्को, लन्दन आदि स्थानों पर बुलाए गए। 29 जुलाई, 1946 से 15 प्रकृतवर्, 1946 तक 21 राष्ट्रों का एक सामान्य सम्मेलन हुआ जिसमें विदेश मन्त्री-परिपक्व द्वारा तैयार किए गए शान्ति-सन्धि के प्रारूपों पर विचार किया गया। सन्धि-प्रारूपों के लगभग 60 अनुच्छेद ऐसे थे जिन पर विदेश मन्त्री-परिपक्व एकरात नहीं थी। इन सभी को सामान्य सम्मेलन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, लेकिन विचार-विमर्श का तरीका ऐसा था कि किसी सर्वमान्य समझौते पर पहुँचने की सम्भावना समाप्त हो गई। पेरिस-सम्मेलन यद्यपि प्रसन्न रहा, लेकिन इसमें जो गिफारिषों की गई उन पर विदेश मन्त्री-सम्मेलन में सम्भीरता-पूर्वक विचार किया गया, और उनमें से कुछ को नागू भी किया गया। काफी मतभेद के बावजूद आगिर दिसम्बर, 1946 में परिपक्व द्वारा पाँचों शान्ति-मन्त्रियों के धनित प्रारूप तैयार कर दिए गए जिन पर फरवरी, 1947 में पेरिस में 20 सदस्य प्रथम मित्रराष्ट्रों और पाँच पराजित राष्ट्रों के हस्ताक्षर हो गए। शान्ति-सन्धियों

के अनुसमर्थन के लिए 15 दिसम्बर, 1947 अन्तिम तिथि निश्चित की गई। इस प्रकार यूरोप के अधिकांश भू-भाग पर शान्ति-स्थापना सम्भावना हो सकी।

पाँच शान्ति-सन्धियाँ (Five Peace Treaties)

1. इटली के साथ हुई सन्धि (Peace Treaty with Italy) के अनुसार इटली के अधिकांश उपनिवेश उससे ले लिए गए। इटली के जो प्रदेश फ्रांस से मिले हुए थे, उनमें से कुछ फ्रांस को दे दिए गए। लगभग 3 हजार वर्गमील का क्षेत्र और एड्रियाटिक सागर के कुछ द्वीप इटली से लेकर यूगोस्लाविया को दिए गए। यूनान के निकटस्थ इटली के कई द्वीप यूनान को प्राप्त हुए। ट्रिस्ट को स्वतन्त्र प्रदेश बना दिया गया। इटली को अपने उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। उसे अफ्रीका में लीबिया, इरीट्रिया और सोमालीलैण्ड के अपने उपनिवेश छोड़ने पड़े। उस पर 36 करोड़ डॉलर हर्जाना लादा गया जो 7 वर्षों की अवधि में यूनान, रूस, अल्बेनीनिया, अल्बानिया, यूगोस्लाविया आदि को दिया जाना था। इटली की सैनिक शक्ति पर पर्याप्त प्रतिबन्ध लगा दिए गए। फ्रांसीसी और यूगोस्लाव सीमान्तों पर उसकी किलेबन्दी नष्ट कर दी गई। सन्धि का कुल मिलाकर परिणाम यह निकला कि न केवल इटली के सम्पूर्ण औद्योगिक साम्राज्य का अन्त हो गया बल्कि वह एक तृतीय श्रेणी की शक्ति रह गया।

2. रूमानिया से सन्धि (Peace Treaty with Rumania) के अनुसार उससे बेसरबिया और उत्तरी बकारिना क्षेत्र कर रूस को दे दिए गए। दोब्रुजा का प्रदेश बल्गारिया को मिला। हंगरी से ट्रान्सिलवेनिया लेकर रूमानिया को लौटा दिया गया। यह भी कहा गया कि रूमानिया हर्जाने के रूप 30 करोड़ डॉलर का सामान आठ वर्ष में रूस को दे। इसके अतिरिक्त रूमानिया का काफी निःशस्त्रीकरण भी कर दिया गया।

3. बल्गेरिया के साथ सन्धि (Peace Treaty with Bulgaria) के अनुसार उसकी जनवरी, 1941 की सीमाओं का पुनर्स्थापन हुआ। सन्धि द्वारा इसका कोई प्रदेश नहीं छोड़ा गया अपितु दक्षिणी दोब्रुजा का प्रदेश उसे रूमानिया से प्राप्त हुआ किन्तु उस पर इटली और रूमानिया की भांति विभिन्न सैनिक प्रतिबन्ध लगा दिए गए। यह भी निश्चय हुआ कि बल्गेरिया अपने यूनानी सीमान्त पर किसी प्रकार की रसायी किलेबन्दी नहीं कर सकेगा और 8 वर्षों की अवधि में 45 करोड़ डॉलर यूनान को और 25 करोड़ डॉलर यूगोस्लाविया को क्षतिपूर्ति के रूप में देगा।

4. हंगरी के साथ सन्धि (Peace Treaty with Hungary) के अनुसार उसका ट्रान्सिलवेनिया प्रदेश रूमानिया को और स्लोवाकिया प्रदेश चेकोस्लोवाकिया को वापस दिए गए। हंगरी पर 20 करोड़ डॉलर का हर्जाना भी लगा दिया गया तथा कुछ निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रावधान भी किए गए।

5. फिनलैण्ड के साथ सन्धि (Peace Treaty with Finland) के अनुसार रूस और फिनलैण्ड के बीच 1940 की सन्धि पुष्टि कर दी गई। इस

सन्धि के अनुसार रूस की सीमा से लगे हुए फिनलैण्ड द्वारा 100 करोड़ रुपये आठ साल में रूस को चुकाना निश्चित किया गया। फिनलैण्ड पर सैनिक प्रतिबन्ध भी लगे।

यद्यपि ये पाँचो सन्धियाँ 15 सितम्बर, 1947 से अन्तिम रूप में लागू कर दी गईं, तथापि इनका पूरी तरह पालन नहीं किया गया। इनके अनेक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ अथवा उनकी उपेक्षा की गई। इन सन्धियों के विरुद्ध 'सशोधन-आन्दोलन' का सूत्रपात हुआ। कालान्तर में सन्धियों के अनेक भाग मृतप्रायः हो गए और कुछ में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।

आस्ट्रिया के साथ सन्धि (Peace Treaty with Austria)

युद्धोपरान्त आस्ट्रिया में, जर्मनी की भाँति ही, सैनिक शासन की स्थापना की गई। आस्ट्रिया की राजधानी वियना को चार भागों में बाँट दिया गया। प्रत्येक भाग पर एक-एक मित्रराष्ट्र का अधिकार स्थापित हुआ। 1955 के प्रारम्भ तक आस्ट्रिया का प्रश्न अक्षर में लटका रहा। बाद में काफी विचार-विमर्श के बाद 15 जुलाई, 1955 को आस्ट्रिया के साथ शांति-सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए। इस सन्धि द्वारा 12 मार्च, 1938 के बाद 17 वर्ष तक पराधीन रहने के पश्चात् आस्ट्रिया की स्वाधीनता एवं सर्वोच्च सम्प्रभुता प्राप्त हुई, किन्तु उसके द्वारा यह वचन दिया गया कि वह जर्मनी के साथ किसी प्रकार का राजनीतिक या आर्थिक मंच नहीं बनाएगा।

जापान के साथ सन्धि (Peace Treaty with Japan)

आत्म-समर्पण के उपरान्त जापानी प्रदेश पर मित्रराष्ट्रों का सैनिक अधिकार स्थापित हुआ, पर वास्तव में वह अमेरिका के पूर्ण नियन्त्रण में ही रहा क्योंकि उसने ही अधुषम गिरा कर जापान को जीता था। 1947 के बाद तो जापान में केवल अमेरिकी सेना ही रह गई और जनरल मैकआर्थर वहाँ का सर्वोन्मथा बन गया। विजेता राष्ट्रों में जापान के भविष्य के बारे में गहरे मतभेद होने से एक लम्बे समय तक उसके साथ सन्धि-वार्ता नहीं की जा सकी। अन्त में जनवरी, 1951 में अमेरिकी विदेशमन्त्री ने विभिन्न राष्ट्रों से परामर्श करके सन्धि का प्रारूप तैयार किया जिसके अनुसार—(1) जापान की सर्वोच्च सत्ता और प्रभुता केवल 4 बड़े और कुछ छोटे द्वीपों के एक लाख पचास हजार वर्ग मील के क्षेत्र तक ही सीमित कर दी गई, (2) जापान ने कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकार की, फारमोसा और बूगटल सत्तारक्षित टापुओं पर अपने अधिकार का परित्याग कर दिया और प्रशासन महामानर में वीनिज व रयूकू टापुओं पर 2 अप्रैल, 1947 से अमेरिका की ट्रस्टीशिप स्वीकार करली, (3) जापान ने चीन में अपने सब अधिकारों को छोड़ना और मित्रराष्ट्रों के युद्ध-अपराध न्यायालय के निर्णयों को मानना स्वीकार कर दिया, एवं (4) जापान ने युद्ध के पूर्व लिए ऋणों के भुगतान का दायित्व भी स्वीकार किया। सन्धि में और भी अनेक बातें विस्तार से सम्मिलित की गईं। 8 सितम्बर, 1951 को इस सन्धि पर 48 राज्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। रूस, पोलैण्ड और

चेकोस्लोवाकिया इससे अलग रहे। सन्धि 28 अप्रैल, 1952 से लागू हुई। अक्टूबर, 1946 में एक पृथक् समझौते द्वारा रूस और जापान के बीच युद्ध-स्थिति का अन्त हो गया, तथापि अभी तक दोनों के बीच कोई औपचारिक शान्ति-सन्धि सम्पन्न नहीं हो सकी है।

जर्मनी के साथ सन्धि वार्ता (Peace Treaty with Germany)

आत्म-समर्पण करने समय जर्मनी में एडमिरल डायनिट्स की अन्तर्कालीन सरकार सत्तारुढ़ थी। मित्रराष्ट्रो ने इस सरकार को मान्यता न देकर जर्मनी का शासन-भार स्वयं सम्भालने का निश्चय किया। जर्मनी को चार भागों में बाँटकर एक-एक भाग का शासन अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्राँस और रूस को मीप दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार पूर्वी जर्मनी पर अमेरिका का, फ्राँस से मिले हुए भाग पर फ्राँस का और बेल्जियम तथा हॉलैण्ड की सीमा से मिले हुए जर्मन प्रदेशों पर इंग्लैण्ड का अधिकार हो गया। पूर्वी जर्मनी पर रूस का कब्जा हो जाने से बर्लिन के चारों ओर का प्रदेश रूसी कब्जे में आ गया पर खास बर्लिन की भी चार भागों में बाँट कर अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्राँस और रूस का अलग-अलग शासन स्थापित किया गया। इस तरह सम्पूर्ण जर्मनी में मित्रराष्ट्रो का सैनिक शासन स्थापित हो गया। हजनि के रूप में जर्मनी पर एक भारी रकम लाद दी गई।

जर्मनी के पुनर्निर्माण के प्रश्न पर एक ओर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस तथा दूसरी ओर रूस के बीच मतभेद इतने अधिक व्यापक और उग्र हो गए कि जर्मनी के साथ कोई सन्धि नहीं की जा सकी। जनवरी, 1947 में ब्रिटेन और अमेरिका ने द्वि-क्षेत्र (Bi-zon a) का निर्माण कर लिया और 31 मई, 1948 को फ्राँस के साथ मिलकर उन्होंने अर्थात् अमेरिका, ब्रिटेन व फ्राँस तीनों ने अपने तीनों क्षेत्रों (Tri-zonia) के लिए एक केन्द्रीय सरकार बनाना स्वीकार कर लिया। 21 सितम्बर को पश्चिमी जर्मनी में सघीय गणराज्य (Federal Republic of Germany) की स्थापना हुई जो अब तक चला आ रहा है और जिसकी राजधानी बोन (Bonn) है। मित्रराष्ट्रो के सैनिक कमीशन ने पश्चिमी-जर्मनी के इस सघीय गणराज्य को प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए। दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में सोवियत संघ ने 7 अक्टूबर, 1949 को जर्मन जनतान्त्रिक गणराज्य (German Democratic Republic) की स्थापना की जिसकी राजधानी सोवियत क्षेत्र के बर्लिन नगर में स्थित है।

अभी तक जर्मनी के साथ कोई शान्ति-सन्धि सम्पन्न नहीं हो सकी थी अतः वैधानिक रूप में जर्मनी और मित्रराष्ट्रो के बीच युद्ध-स्थिति थी। 1951 में पश्चिमी राज्यों ने अपनी ओर से जर्मनी के साथ युद्ध-समाप्ति की घोषणा कर दी और मई, 1952 में पश्चिमी जर्मनी को व्यावहारिक स्वशासन प्रदान कर दिया। मई, 1955 में 'जर्मन-सघीय-गणराज्य के मौलिक कानून' (Basic Laws of the Federal Republic of Germany) की पश्चिमी क्षेत्रों के मित्रराष्ट्रीय मंत्रि-मन्त्रों ने स्वीकार कर लिया। इस अधिनियम द्वारा पश्चिमी जर्मनी पर से पश्चिमी

राष्ट्रों ने अपने मैनिक अधिकार समाप्त कर दिए और उन प्रकार सशस्त्र गणराज्य को स्वाधीनता तथा सर्वोच्च सप्रभुता प्राप्त हो गई। मोवियन सघ ने भी 20 मिनट्स, 1955 को एक सन्धि द्वारा पूर्वी जर्मनी के जनतान्त्रिक गणराज्य को पूर्ण स्वाधीनता और प्रभुता प्रदान कर दी जो वास्तव में मंडानिक ही थी क्योंकि व्यावहारिक रूप से मोवियन सघ का पूर्वी जर्मन सरकार पर पूरा नियंत्रण रहा।

जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न आज भी अंधरे में लटका हुआ है, तथापि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के सम्बन्धों में सुधार जारी है। सितम्बर, 1971 में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने बर्लिन-समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि पश्चिमी बर्लिन के लोगों को पूर्वी बर्लिन और पूर्वी जर्मनी जाने की छूट होगी तथा बर्लिन-प्रवेश के सम्बन्ध में पूर्वी जर्मनी में होकर बेरोकटोक और सीधे-सामान्य रूप से यातायात चालू होगा। कुछ और भी व्यवस्थाएँ की गईं जिससे दोनों पक्षों के सम्बन्धों को अच्छा बनाया जा सके। नवम्बर, 1972 में दोनों जर्मन राज्यों में एक सन्धि सम्पन्न हुई जिसमें दोनों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर जर्मन-समस्या के समाधान के लिए, बल-प्रयोग के उपयोग को निषेधित दे दी। दोनों संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य भी बन गए हैं।

आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण

(Economic Recovery and Integration)

यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण, विकास और एकीकरण करने के लिए पश्चिमी शक्तियों द्वारा जो प्रस्ताव किए गए उन्हें विभिन्न कारणों से मोवियन रूस तथा उसके साथी राष्ट्रों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कतम्बरूप ऐसा कोई नामान्य कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सका जिसके द्वारा यूरोप के सभी राष्ट्रों का आर्थिक विकास हो सके। इन दोनों ही पक्ष अपने-अपने गुट के देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अलग-अलग योजनाएँ बनाने लगे, महाद्वीप विभाजित हो गया तथा क्षेत्रीय आधार पर क्षति-पूर्ति के प्रयास किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका मार्शलवाद के विरुद्ध ऐसे सगठनों को आत्मरक्षा के लिए बड़ा उपयोगी समझता था। अतः 1951 के पारस्परिक सुरक्षा कानून (The Mutual Security Act) में यूरोप का आर्थिक और राजनीतिक सघ बनाने के लिए अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। मूलपूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री चर्चिल ने यूरोप की एकता के आन्दोलन का 1964 में ही सूत्रपात कर दिया था। सभी प्रयत्नों के कतम्बरूप पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण के लिए जो कार्यक्रम और सगठन अस्तित्व में आए, उनमें से प्रमुख ये हैं—

बेनेलक्स (Benelux)

यूरोप के देशों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का यह प्रथम महत्वपूर्ण कदम था। यह सन्धि बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग के बीच मिनम्बर, 1944 में ही हो गई थी। जनवरी, 1948 में इसे मजबूत रूप से स्वीकार किया गया। इस सन्धि द्वारा इसके भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों के बीच खुशी की पूरी तरह

समाप्त कर दिया गया तथा आयात पर एक समान टैटिफ कार्यक्रम की स्थापना की गई। कहा जाता है कि इस सन्धि का अन्तिम लक्ष्य पूर्ण आर्थिक-संघ का निर्माण करना था। तीनों देशों के विदेश मन्त्रियों ने 1 जनवरी, 1950 को इस प्रकार का संघ प्रारम्भ करने की निधि निश्चित की और बाद में इस तिथि को कई बार स्थगित कर दिया गया क्योंकि इसे क्रियान्वित करने के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ थी। बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब तक कुछ बड़े उद्योगों के विशेष हितों को, यहाँ तक कि राष्ट्रीय हितों को भी अधीनस्थ या गौण नहीं बना दिया जाता तब तक पूरे यूरोप के आर्थिक लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

मार्शल योजना (Marshall Plan)

इस योजना का उद्देश्य युद्ध-ध्वस्त यूरोप का पुनरुद्धार कर उसको साम्यवाद से बचाना था। अपने 5 जून, 1947 के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध भाषण में अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्शल ने कहा, "हमारी नीति किसी देश या सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, यह भूख, दरिद्रता, निराशा और अव्यवस्था के विरुद्ध है। इसका उद्देश्य विश्व में एक ऐसी अव्यवस्था की स्थापना करना है, जिसमें स्वतन्त्र समस्याओं को विस्तारित करने वाली राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकें।"

पश्चिमी देशों के राष्ट्रों ने मार्शल-योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ब्रिटेन और फ्रांस की पहल पर जुलाई, 1947 में पेरिस में 16 यूरोपीय देशों इंग्लैंड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, नार्वे, लक्जमबर्ग, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड और टर्की के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति (Committee of European Economic Co-operation) की स्थापना की गई और यूरोपीय पुनरुद्धार का चार वर्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया।

यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति ने समुत्तराज्य अमेरिका को एक रिपोर्ट अर्पित की जिसमें कहा गया कि अमेरिका यदि 29.3 बिलियन डॉलर धन-राशि भर्त्ता करने को तैयार हो तो 1951 तक एक आत्म-निर्भर यूरोपीय अर्थव्यवस्था (Economy) की प्राप्ति की जा सकती है। यह रिपोर्ट 'मार्शल योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई। दिसम्बर, 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 'मार्शल योजना' से सम्बन्धित व्यय का अनुमान कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें सवा चार वर्ष की अवधि के लिए 17 अरब डॉलर और 15 महीनों के लिए 6 अरब 80 करोड़ डॉलर के व्यय का अनुमान लगाया गया। इस प्रस्ताव के उद्देश्य (Motive) की व्याख्या करते हुए ट्रूमैन ने कहा—“मेरा प्रस्ताव यह है कि अमेरिका उन 16 राज्यों को जो उसी की तरह स्वतन्त्र समस्याओं की मुरझाएँ एवं राष्ट्रों के बीच स्थायी शान्ति के लिए दृढ़ मन्त्र्य है, उनके पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता देकर विश्वशान्ति एवं अपनी सुरक्षा में योगदान करे।”

‘मार्शल योजना’ को जो अधिकृत रूप से ‘यूरोपीय रिलीफ प्रोग्राम’ (European Relief Programme) के नाम से प्रसिद्ध हुई, वास्तव में स्वीडन

कर दिया। 3 अप्रैल, 1948 को कांग्रेस ने 'विदेशी सहायता अधिनियम' पारित कर मार्शल योजना को मूल रूप प्रदान किया और इसको कार्यान्वित करने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन' (Organization for European Economic Co-operation) की स्थापना की गई।

मार्शल योजना "समसामयिक कूटनीतिक इतिहास की सर्वाधिक दिलचस्प और युग-प्रवर्तक घटनाओं में से एक थी" जिससे रूस और पश्चिम का विरोध पहले की अपेक्षा और भी अधिक उग्र हो गया। इस योजना के अन्तर्गत चार वर्षों (1947-1952) में अमेरिका ने यूरोप को लगभग 11 बिलियन डॉलर की सहायता दी। इस योजना के कारण एक ओर तो पश्चिमी यूरोप आर्थिक पनन और साम्यवादी आधिपत्य से बच गया तथा दूसरी ओर संयुक्तराज्य अमेरिका पाश्चात्य जगत् का सर्वमान्य नेता बन गया। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देते हुए यह शर्त लगाई कि वे अपनी सरकारों में साम्यवादी तत्त्वों का उन्मूलन करेंगे।

मार्शल योजना एक प्रकार से ट्रूमैन सिद्धान्त का ही विकसित रूप थी जिसने ट्रूमैन सिद्धान्त में प्रतिपादित 'प्रवरोध की नीति' को तीन प्रकार से आगे बढ़ाया—

(i) जहाँ ट्रूमैन सिद्धान्त में अलग-अलग राज्यों को सहायता देने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ मार्शल योजना में यूरोप को समग्र रूप से सहायता देने की व्यवस्था की गई।

(ii) मार्शल योजना ने 'प्रवरोध की नीति' में आर्थिक तत्त्वों के महत्त्व को भली प्रकार स्पष्ट कर दिया।

(iii) इसके द्वारा पहली बार अमेरिकी आर्थिक सहायता को एक सहयोगी एवं योजनाबद्ध रूप दिया गया।

पश्चिमी यूरोप में मार्शल योजना के द्वारा बढ़ते हुए राजनीतिक आघात को देखते हुए, रूस भी पूर्वी यूरोप के लिए 'मोलोतोव योजना' बनाने के लिए मजबूर हुआ और 1949 में मास्को में 'पारस्परिक आर्थिक सहायता-परिपद' की स्थापना की गई। उस समय निश्चय ही रूस अपने पिछले ग़रीब राष्ट्रों को कुछ मदद तो नहीं दे सक्ता, लेकिन वह जो शोषण कर रहा था उसमें कुछ कमी जरूर हुई। पुरानी अल्पव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के स्थान पर पूर्वी यूरोप के राज्यों में एक अर्द्ध-राजकीय नियोजन क्रिया गया, लेकिन इसमें पश्चिमी यूरोप के आर्थिक सहयोग का मुकाबला नहीं हो सका।¹

पश्चिमी यूरोप के अपेक्षाकृत सीमित दायरे में सोवियत रूस द्वारा प्रवरोध-कार्यवाहियों के बावजूद मार्शल योजना को विशेष सफलता प्राप्त हुई। ब्रून एवं मैमटे (Brunn and Mamatey) के पूर्वावलोकन के अनुसार "1 जून, 1952 को जब यह योजना समाप्त हुई, तब इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों के उत्पाद, मुनियोजन तथा अमेरिकी उदारता में पश्चिमी यूरोप आर्थिक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में बेवज्र आत्म-निर्भर हो नहीं सका, यद्यपि उनमें समृद्धि भी प्राप्त थी। पश्चिमी यूरोप में

आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में जो सामूहिक प्रयास किए गए उनका परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था अधिक संगठित रूप में अमेरिकी अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध हो गई और आर्थिक-संगठन ने 'राजनीतिक संगठन' सम्बन्धी प्रयत्नों को आगे बढ़ाया। अन्तर्यूरोपीय-परिपक्षों में एक-दूसरे के सम्पर्क में आने से पश्चिमी यूरोप के राजनीतिज्ञों ने एक-दूसरे की निकटता से समझा और सहयोग से काम करना सीखा। पश्चिमी यूरोप ने संगठन, दृढ़ता और एकता की उस भावना को विकसित किया जो शायद शार्लमेन के बाद महसूस नहीं की गई थी। दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बीच विरोध की खाई बढ़ती गई। यूरोप की एकता के पुराने आदर्श का स्थान एक नई वास्तविकता ले रही थी—उत्तरी अतलान्तिक संगठनों की वास्तविकता।”

यूरोपीय परिषद् (The Council of Europe)

यूरोपीय इतिहास का यह एक क्रूर व्यापार है कि जिन लोगों ने विश्व की सबसे महान् और अपूर्व सम्यता का निर्माण किया है तथा अपनी विजय, उपनिवेश-वादी नीति एवं व्यापार से विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ा, वे स्वयं विभाजित और कई बार आपसी युद्ध में सलग्न हुए। द्वितीय महायुद्ध के बाद स्थिति यह बन गई कि पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव के प्रसार और पश्चिमी यूरोप को अमेरिका द्वारा सैनिक-आर्थिक सहायता से ग़्रुप के राष्ट्रीय राज्यों की सार्वभौम सत्ता और स्वतन्त्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। जब पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक स्वतन्त्रता खतरे में थी तभी स्पष्ट हुआ कि पश्चिमी यूरोप आर्थिक पतन की ओर भी अग्रसर है। निषेध-व्यापार में यूरोपीय राष्ट्रों का हिस्सा 1938 में 50% से गिरकर 1948 में 40% में भी कम रह गया और उनकी यह हानि अमेरिका के लिए लाभकारी थी क्योंकि इन दस वर्षों में अमेरिका ने विश्व-व्यापार में अपने हिस्से को 15% से बढ़ाकर 25% कर लिया था। पश्चिमी यूरोप के इस आर्थिक पराभव का एक मुख्य कारण यह था कि यूरोपीय राष्ट्र आपसी प्रतियोगिता, मुद्रा की विविधता, प्रतिरोधक चुँगी की दीवारों और विरोधी नीतियों में शिकार थे। इसके अनिरिक्त एशिया और अफ्रीका में स्थित उनके भूतपूर्व उपनिवेश तेजी से उनके हाथों से निकलते जा रहे थे।

इन परिस्थितियों में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता थी और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने अनुभव किया कि “रून और अधिक प्रदेश न हूब से, इसके लिए उन्हें आपसी सैनिक सहयोग तथा अपने साधनों को विकसित करने और सामूहिक बाजार के लिए अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है।” पश्चिमी यूरोप की जनता निकट सम्बन्ध स्थापित करना चाहती थी, इसका प्रमाण 1949 में मिला जब 10 देशों ने ‘यूरोपीय परिषद्’ (Council of Europe) का निर्माण करना स्वीकार कर लिया। ये 10 देश थे—ब्रिटेन, फ्राँस, इटली, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, नार्वे तथा स्वीडन। 1949 के प्रारम्भ में यूनान और टर्की ने, 1950 में आइसलैंड ने और 1951 में जर्मन-सम राज्य ने इसमें प्रवेश किया। 1955 में आस्ट्रिया के प्रवेश के साथ ही इसके सदस्यों की संख्या 15 हो गई।

1949 में पारित प्रारूप की, जिसमें 'यूरोपीय परिषद्' के उद्देश्य और नक्ष्य निर्धारित किए गए थे, प्रथम धारा का प्रथम वाक्य इस प्रकार था—

"यूरोपीय परिषद् का उद्देश्य अपने सदस्यों में अधिकाधिक एकता स्थापित करना है जिसमें वे अपने सदस्य-राज्यों के समान परम्परागत आदर्शों एवं सिद्धान्तों की रक्षा कर उन्हें साकार कर सकें तथा अपनी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को गति प्रदान कर सकें।"

इस घोषणा के महत्त्व को तो इस बात में आंका जा सकता था कि इस प्रस्तावित उद्देश्य के लिए सदस्य कितनी दृढ़ता एवं निश्चय प्रदर्शित करते हैं। 'अपने समान परम्परागत आदर्शों एवं सिद्धान्तों' द्वारा स्पष्ट ही सदस्य-राष्ट्रों की स्वतन्त्रता एवं जनतान्त्रिक जीवन-पद्धति पर जोर दिया गया था। तीसरी धारा में इस बात को अधिक स्पष्ट शब्दों में घोषित किया गया—

"यूरोपीय परिषद् के प्रत्येक सदस्य को कानून के शासन के सिद्धान्तों को मानते हुए यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसके शासन-क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मानवीय अधिकारों और भूलभूत स्वतन्त्रता के उपयोग का अधिकार है।"

1949 में यूरोपीय परिषद् का निर्माण आंशिक रूप से अमेरिकी दबाव के प्रति प्रतिक्रिया तथा आंशिक तौर पर उसके प्रति सहमति थी। जब 1949 में अमेरिका की कांग्रेस ने 'यूरोपीय पुनर्रचना कार्यक्रम' के लिए 5 अरब डॉलरों की स्वीकृति दी तब अमेरिकियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें आशा है कि जो यूरोपीय राष्ट्र यह महायत्ना स्वीकार करेंगे वे अपने पृथक् व्यक्तित्व एवं लिहित स्वाध्यायों में अधिक समस्त पश्चिमी यूरोप के कल्याण को प्राथमिकता देंगे। अमेरिका द्वारा महायत्ना देने में पहले यह खतरा दूर करना जरूरी था कि विविध राष्ट्र इसमें राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बटावा नहीं देंगे। फलस्वरूप अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज सी मार्शल ने यूरोपीय पुनर्रचना-कार्यक्रम को समन्वित रूप देने के लिए 'यूरोपीय आर्थिक-मध्यम-संगठन' की स्थापना की जिसे 1960 में 'आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन' का नाम दिया गया। वास्तव में यह बात स्पष्ट थी कि 'यूरोपीय एकीकरण' सम्बन्धी अमेरिका का प्रोत्साहन तभी सफल हो सकता था जब स्वयं यूरोपीय राष्ट्र उसे स्वीकार करके कार्य रूप में परिणत करते। यूरोपीय परिषद् की स्थापना में ऐसा प्रतीत हुआ कि पश्चिमी यूरोप के लोग एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाथिश रूप में उन्मुख थे लेकिन जो परिणाम निकले वे काफी निराशाजनक थे और 'यूरोपीय परिषद्' वास्तविक न होकर छाया मात्र मिट्टी हुई। बहुत एवं मैने के अनुसार, यूरोपीय सरकारों ने मार्शल योजना के अन्तर्गत महायत्ना तो प्रारंभ की, लेकिन चुगौली की दरा में कमी करने में तथा सामा बाजार (कॉमन मार्केट) की स्थापना में देरी की। तीन वर्ष तक मार्शल योजना के अन्तर्गत महायत्ना लेने के बाद भी यूरोपीय राज्यों ने आर्थिक एकीकरण की ओर बहुत कम प्रगति की जिसके फलस्वरूप पाउ जी, हाफमैन ने, जो इस महायत्ना के किरण की निगरानी के लिए नियुक्त थे, 1951 में अग्रान्त होकर घोषणा की—

“यदि पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र पूर्व की ओर से खतरा होते हुए भी तथा मार्शल योजना के अन्तर्गत 5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने पर भी आर्थिक दृष्टि से एक नहीं हो सकते, तो मुझे इस बात में सन्देह है कि वे कभी भी एक नहीं हो सकेंगे।”

1961 में साइप्रस को भी यूरोपीय परिषद् की सदस्यता दे दी गई। इसका प्रधान कार्यालय स्ट्रासबर्ग में है, इसकी एक मन्त्रि-परिषद् और एक परामर्शदात्री सभा है। यद्यपि अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में तो इसकी प्रगति उत्साहजनक नहीं मानी जा सकती, तथापि यह स्वीकार करना होगा कि यूरोपीय राष्ट्रों के बीच एकता कायम करने तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करने में इसने अपनी भूमिका निभाई।

सीमित क्षेत्रों में सहयोग

महामुद्र के पश्चात् यद्यपि बड़े पैमाने पर ‘यूरोपीय एकीकरण’ में देर हुई, लेकिन कई सीमित क्षेत्रीय समझौते सम्पन्न हुए। बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स और लक्जमबर्ग के बीच जो ‘बेनेलक्स’ मन्धि हुई उसका उल्लेख किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सीमित क्षेत्रीय समझौतों में ‘यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय’ (European Coal and Steel Community) ‘युरैटम’ (EURATOM), ‘यूरोपीय माझा बाजार’ (European Common Market ECM), ‘यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार परिषद्’ (European Free Trade Association EFTA) उल्लेखनीय है।

1. मिनम्बर, 1950 में ‘यूरोपीय भुगतान संघ’ की स्थापना हुई जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन से सम्बद्ध था और जिसका उद्देश्य अन्तर्-यूरोपीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना था। दिसम्बर, 1958 में पश्चिमी यूरोप की मुद्रा-व्यवस्था में संगठनात्मक परिवर्तन करते समय इसका अन्त कर दिया गया।

2. 1951 में 6 यूरोपीय देश अपने कोयले, लोहे और इस्पात के उत्पादन के प्रयामों को समन्वित करने को सहमत हो गए और 10 अगस्त, 1952 को ‘यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय’ अस्तित्व में आया जिसके 6 सदस्य थे—बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स, लक्जमबर्ग, फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी। ‘समुदाय’ के मचालन के लिए एक मन्त्रि-परिषद्, एक सभा तथा एक न्यायालय की स्थापना हुई। ‘समुदाय’ के सदस्य-राज्यों के लिए एक सम्मिलित बाजार की व्यवस्था की गई है और उन्हें कोयला तथा इस्पात के साधन समान शर्तों पर प्राप्त होने की सुविधा है। सदस्य राज्यों के बीच भेदभाव की नीति का बहिष्कार किया गया है।

3. 1957 में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग तथा नीदरलैण्ड्स ने आणविक शक्ति के शान्तिकालीन प्रयोग के प्रयामों को विकसित करने के लिए समझौता करना स्वीकार किया जो ‘यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय’ अर्थात् ‘युरैटम’ (EURATOM) के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी, 1958

से यह समझीता लागू है। सदस्य-राज्यों में पाए जाने वाले यूरैनियम और थोरियम पर समुदाय का प्राथमिक अधिकार होता है और समुदाय बिना किसी भेदभाव के इनका वितरण अणुशक्ति प्रतिष्ठानों के बीच करता है। 'यूरेटम' को ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा का समर्थन और सहयोग प्राप्त है।

4. यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा साझा बाजार (European Common Market) की स्थापना 1 जनवरी, 1958 को की गई जिसका उद्देश्य सदस्य-देशों का आर्थिक एकीकरण करना तय हुआ। पहले इसके सदस्य-देश बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और लक्जमबर्ग थे, लेकिन 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन के शामिल हो जाने पर सदस्य-देशों की संख्या 9 हो गई। 1 जनवरी, 1981 को यूनान उसका 10वाँ सदस्य बन गया। बाद में ब्रिटेन भी इसका सदस्य बन गया। अफ्रीका के अनेक राष्ट्र इसके सह-सदस्य (Associate Members) हैं। साझा बाजार का उद्देश्य बड़े पैमाने की उत्पादन-प्रणाली द्वारा उत्पादन कर, विशिष्टीकरण और थम-विभाजन के लाभ प्राप्त करना है। साझा बाजार में सदस्य-राष्ट्रों को यद्यपि बड़े पैमाने के विशाल आर्थिक लाभ उपलब्ध हुए हैं, तथापि इस प्रकार की योजनाएँ वस्तुतः सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता और मुक्त-व्यापार के हितों के लिए घातक हैं।

पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा (The Military Security of Western Europe)

यूरोप की आधुनिक उन्नति के साथ ही यह भी आवश्यक था कि उसे सैनिक रूप से भी सशक्त बनाया जाए। पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा न होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि यूरोप के इन दोनों भागों के बीच संयुक्तराज्य अमेरिका की सेनाएँ रखी जाएँ आर्थिक क्षेत्र की भाँति यूरोप के देशों को सैनिक दृष्टि से भी एकीकृत करने के प्रयास हुए—

डंकर्क सन्धि (Dunkirk Treaty)—यह सन्धि ग्रेट-ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य 4 मार्च, 1947 को 50 वर्ष के लिए की गई। इसका प्रयोजन सम्भावित आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक सैनिक सहायता है। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने यह निश्चय किया कि (क) जर्मनी के आक्रमण करने पर, (ख) जर्मनी द्वारा आक्रमण को प्रोत्साहित करने की नीति स्वीकार करने पर, एवं (ग) संयुक्त राष्ट्रमण्डल द्वारा जर्मनी के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने पर दोनों देश एक-दूसरे को सैनिक तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध करेंगे। इस सन्धि के द्वारा दोनों ही देशों ने एक-दूसरे को यह भी आश्वासन दिया है कि वे दोनों एक-दूसरे को निरन्तर आधुनिक सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

ब्रुसेल्स की सन्धि (Brussels Treaty)—ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और हाल्लैंड द्वारा 17 मार्च, 1947 को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग एवं सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य से 50 वर्ष के लिए यह सन्धि की गई जिसके

अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में से किसी पर भी आक्रमण होगा तो सदस्य-देश समुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की धारा 51 के अनुसार उसकी सहायता करेंगे। यू.सेन्स सन्धि में 10 धाराएँ हैं। सन्धि के प्रमुख ध्येय इस प्रकार हैं—मूलभूत अधिकारों में विश्वास की पुष्टि तथा संध के चार्टर में उल्लिखित आदर्शों की पुष्टि, जनतन्त्र एवं स्वतन्त्रता का स्थापित्व; पुनर्गठन में सहयोग; अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में सहयोग, युद्ध-नीति के विरुद्ध मोर्चा, आदि। 1954 में पेरिस के सम्मेलन में पश्चिमी जर्मनी और इटली भी यू.सेन्स-सन्धि सगठन में सम्मिलित हो गए और इस सगठन का नया नाम 'पश्चिमी यूरोपीय सन्धि' (Western European Treaty) रखा गया।

नाटो (NATO)—सोवियत साम्राज्यवाद के भय तथा सोवियत आक्रमण के समय संयुक्त राष्ट्रसंघ से पर्याप्त सहायता न पा सकने की सम्भावना की भावना से प्रेरित होकर ही 4 अप्रैल, 1948 को वाशिंगटन में—अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैण्ड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैण्ड (हॉलैण्ड), नाइ और पुर्तगाल इन 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिए। 24 अगस्त, 1949 को सम्बन्धित सदस्य-राज्यों द्वारा इस संगठन का अनुगमन कर देने पर इसकी विधिवत् स्थापना की गई। फरवरी, 1952 में यूनान और टर्की तथा मई, 1955 में पश्चिमी जर्मनी के शामिल हो जाने से इस संगठन के कुल 15 सदस्य हो गए।

सन्धि-संगठन के चार्टर में 14 धाराएँ रहीं गईं, लेकिन इनका सम्पूर्ण भार पौचवी धारा में प्राप्त होता है जो इस प्रकार है—“सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष इन बातों में एकमत हैं कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में से किसी एक अथवा अधिक के विरुद्ध आक्रमण सभी के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा। इर्मीलिए के इस बान पर सहमत होते हैं कि यदि किसी प्रकार का मशरय आक्रमण होता है तो उनमें से प्रत्येक समुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के 51वें अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आत्म-रक्षा के अधिकार के अनुसार कार्य करते हुए, शीघ्र ही व्यक्तिगत रूप में तथा अन्य दलों के साथ मिलकर इस प्रकार से आक्रान्त दल या दलों की सहायता करने के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह आवश्यक समझे। इसमें उत्तरी अटलाण्टिक क्षेत्र में सुरक्षा की पुन स्थापना के लिए मजबूत शक्ति का प्रयोग भी सम्मिलित है।” नाटो सन्धि के बाकी अनुच्छेदों में सन्धि-कर्ताओं के आर्थिक सहयोग और सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध की क्षमता का विकास करने आदि का उल्लेख किया गया।

नाटो सन्धि सगठन के तीन प्रमुख क्षेपण क्षेत्र हैं—

1 यूरोपीय कमान क्षेत्र—इसमें नार्थ कोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका और अटलाण्टिक से तुर्की की पूर्वी सीमा तक का सारा यत्न सम्मिलित है। ब्रिटेन, पुर्तगाल तथा अफ्रीरिया को इनमें घुसकू रखा गया है। यह क्षेत्र यूरोप के सर्वोच्च कमान्डर के अधीन होता है।

2. अटलाण्टिक कमान क्षेत्र—समस्त अटलाण्टिक सागर, उत्तरी प्रब से ट्रापिक ऑफ कैसर और उत्तरी अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका तक का सारा समुद्री क्षेत्र इस कमान के अन्तर्गत शामिल है, केवल ब्रिटेन तथा इसी खाड़ी के क्षेत्र के शीप इसमें शामिल हैं।

3 ब्रिटिश खाड़ी कमान-क्षेत्र—इस कमान में ब्रिटिश खाड़ी तथा उत्तरी सागर के दक्षिणी क्षेत्र का समावेश है। खाड़ी क्षेत्र की कमान समिति में बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैण्ड तथा ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष सम्मिलित हैं।

नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। मन्धि-संगठन उत्तरी अमेरिका के दो प्रमुख देशों—संयुक्तराज्य अमेरिका तथा कनाडा को पश्चिमी यूरोप के भाव सैनिक गठबन्धन में संयुक्त करता है।

नाटो संगठन अपने मूल रूप में साम्यवादी जगत् के लिए एक चेतावनी है कि वह मन्धि में सम्मिलित किसी देश पर आक्रमण करने का साहस न करे। यह मन्धि यूरोपीय देशों को एक सुरक्षा-आवरण प्रदान करती है जिसके द्वारा वे अपने आर्थिक और सैनिक अधिकारों के कार्यक्रम पूरे कर सकें। साथ ही यह मन्धि अमेरिका को किसी भी साम्यवाद-विरोधी युद्ध के लिए सदैव तैयार रहने की प्रेरणा करती है। नाटो मन्धि-संगठन में कई बार फूट के जबरदस्त लक्षण पैदा हुए और फ्रांस के सर्वे ने मन्धि-संगठन के टूटने का खतरा तक पैदा कर दिया, लेकिन संगठन मरटो को पार कर गया। जून, 1974 के 'नाटो सम्मेलन' में नाटो मन्धि संगठन के उद्देश्य-पत्र को शान्तिपूर्ण सहस्रस्तित्व की दृष्टि से एक नया रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन यह केवल 'हाथी के दाँत पाने के और दिवाने के और' वाली बात थी, अन्यथा नाटो का मूल रूप वही पहले जैसा बना रहा। जून, 1974 का यह नाटो-सम्मेलन वास्तव में 'यूरोप के अमेरिकीकरण' का एक प्रयास था। संयुक्त विज्ञापन में यह बात दुहराई गई कि नाटो अपने सदस्य-देशों के बीच ही नहीं, बल्कि मरटो के सभी देशों के बीच शान्ति और सहभाव स्थापित करने के लिए काम करेगा। यह स्पष्ट कर दिया गया कि संयुक्त रक्षा कार्यक्रम पहले ही की तरह नाटो का एक मजबूत आधार बना रहेगा। नाटो उद्देश्य-पत्र में फ्रांस की मनुष्ट करने का सबसे अधिक प्रयत्न किया गया और जिन बातों को लेकर अमेरिका तथा फ्रांस के सम्बन्धों में तनाव था उन्हें छोड़ दिया गया। नाटो उद्देश्य-पत्र की शब्दावली चाहे कितनी ही आकर्षक थी, यह असन्तुष्टि दायी नहीं रह मरी कि नाटो के सदस्य-देश सैनिक महत्वाकांक्षाओं में पूर्णतः प्रभावित हैं। उद्देश्य-पत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि नाटो के वाटर, विशेषकर पश्चिमी एशिया की घटनाओं में मिट्ट होना है कि नाटो की संयुक्त-रक्षा-व्यवस्था और मजबूत की जानी चाहिए। उद्देश्य-पत्र में स्वीकार किया गया कि नाटो की वर्तमान सैनिक शक्ति में यूरोपीय देशों का काफी बड़ा योगदान है। अमेरिका ने इस बात पर महत्प्रति प्रकट की कि वह नाटो के सदस्य-देशों पर किसी भी तरह के सैनिक दबाव का मुकाबला करने के लिए सदैव तैयार है। अमेरिका ने नाटो के

सदस्यों को यह अनुभव कराया कि बिना अमेरिकी सेनाओं के संयुक्त रक्षा कार्यक्रम प्रभावशाली नहीं हो सकता।

नाटो (उत्तर अटलांटिक मैन्य सगठन) पिछले कुछ वर्षों से अनेक गम्भीर समस्याओं का शिकार रहा है और उसकी प्रतिरक्षा व्यवस्था के कुछ ग्रंथ सडखडाते गये हैं। पुर्तगाल, इटली, ग्रीस और टर्की की अस्थिर राजनीति और उनमें से कुछ के नाटो के प्रति अनिश्चित रवैये के कारण अमेरिका और उसके मित्र देशों को यह चिन्ता पड़ी रही है कि नाटो की लौह भित्ति की दरारों को किम प्रकार भरा जाए। नाटो बारसा सगठन के मुकाबले प्राधुनिकनम शस्त्र-सज्जा के लिए प्रयत्नशील रहा है और 1980 में प्रक्षेपास्त्रों के प्राधुनिकीकरण की योजना पर लगभग अन्तिम विचार कर लिया गया था।

यूरोपीय प्रतिरक्षा समुदाय (European Defence Community : EDC)—सम्पूर्ण पश्चिम-यूरोप की प्रतिरक्षा के लिए एक सगठन का निर्माण करने की दृष्टि से 27 मई, 1952 को 50-वर्षीय 'यूरोपीय प्रतिरक्षा समुदाय-सन्धि' पर फ्रांस, पश्चिमी-जर्मनी, नीदरलैंड्स बेल्जियम और लक्जमबर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस सन्धि के द्वारा ही यूरोपीय प्रतिरक्षा-समुदाय का आविर्भाव हुआ जिसके संविधान में यह व्यवस्था की गई कि हस्ताक्षरकर्त्ता राज्य नाटो के संघ्य सगठन में अपनी सेनाओं को एक इकाई की तरह शामिल करेंगे। यूरोपीय प्रतिरक्षा-समुदाय यूरोप के राजनीतिक एकीकरण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन राजनीतिक घटना-चक्र ने इस समुदाय की व्यावहारिक स्थापना सन्दिग्ध बना दी। अगस्त, 1954 में फ्रांस की राष्ट्रीय परिषद् ने उपर्युक्त सन्धि को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् इसके स्थान पर पश्चिमी-यूरोपीय सघ (Western European Union : WEU) का निर्माण हुआ जिसका उल्लेख आगे किया गया है।

पश्चिमी-यूरोपीय संघ (Western European Union : WEU)—लन्दन सम्मेलन में 2 अक्टूबर, 1954 को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा बेनेलक्स देशों (हालैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग) ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर कर पश्चिमी यूरोपीय सघ की स्थापना की। ये देश कम से कम सन् 1998 तक के लिए परस्पर प्रतिरक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए सगठित हो गए। सघ की स्थापना के समय यह निश्चय किया गया कि पश्चिमी-जर्मनी को भी नाटो में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया जाए। बदले में पश्चिमी-जर्मनी ने स्वीकार किया कि वह अपने शस्त्रास्त्रों के उत्पादन पर स्वेच्छा से नियन्त्रण रखेगा। यह भी तय हुआ कि जब तक पश्चिमी-जर्मनी स्वयं अपनी प्रतिरक्षात्मक सेनाएँ तैयार न करले, तब तक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएँ पश्चिमी-जर्मनी और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की रक्षा के लिए वहाँ रहे। संघ की सभी सशस्त्र सेनाएँ नाटो की अध्यक्षता में रखी गईं।

पश्चिमी-यूरोपीय सघ के सदस्यों में शीघ्र ही मतभेद उत्पन्न हो गए और राज-इमजा केवल एक ही काम रह गया है कि यह शस्त्रास्त्रों के नियन्त्रण की देखभाल करे—विशेष रूप से जर्मनी की सैनिक प्रभुता की रोकने के लिए।

नाटो और वारसा सन्धि के देशों द्वारा विश्व-शान्ति वार्ता की श्रोट में अपनी सामूहिक सैनिक-शक्ति में वृद्धि और इस प्रकार निःशस्त्रीकरण की असफलता

अब से कोई तीस वर्ष पहले यह कल्पना करना कठिन था कि पूरी एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन (नाटो) और वारसा सन्धि जैसे सैनिक गुट अपने आपकी सैनिक दृष्टि से इतना मजबूत बना लेंगे कि दोनों को ही एक दूसरे का डर बना रहेगा और इसी डर के कारण विश्व में शान्ति बनी रहेगी। लगभग पिछले आठ वर्षों से यूरोप के सभी शक्तिशाली देश तनावपूर्ण बनाने के प्रयत्नों की बात करते रहे हैं लेकिन इन दो सैनिक गुटों के समाप्त होने की निवृत्त भविष्य में कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती। स्वेच्छा से अस्त्र-शस्त्र और सेनाओं में कमी करने तथा परमाणु अस्त्रों का प्रसार रोकने की पूर्व-पश्चिम की बातचीत के इस दौर में ऐसा कोई सकेत नहीं मिल रहा है कि इन दोनों सैनिक गुटों के देशों की सैनिक तैयारियों में कोई कमी आई है अथवा आएगी। जब इस प्रकार की बातचीत शुरू हुई थी तो विश्व में सभी को आशा थी कि अब विश्व के ये दोनों प्रमुख सैनिक गुट अपनी सैनिक तैयारियों में कमी करके शान्ति स्थापना की वास्तविक इच्छा का कोई प्रमाण देंगे, परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ।

जहाँ तक सैनिक तैयारियों का सम्बन्ध है दोनों गुटों में से कोई भी एक दूसरे की इस समय हरा नहीं सकता। दोनों की सैनिक शक्ति सन्तुलन में घटत-बढ़त होती रहती है। लेकिन दोनों ही इस कमी को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जहाँ तक सैनिक शक्ति के सन्तुलन का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि पूर्व यूरोप के देश टैको के क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं लेकिन नाटो सन्धि के देशों में टैक भारत अस्त्रों का आविष्कार करके उनकी इस श्रेष्ठता को निरर्थक बना दिया है। नाटो सन्धि के देशों ने वायु आक्रमण से रक्षा के लिए आधुनिकतम अस्त्र बनाए हैं, परिणाम-स्वरूप वारसा सन्धि देशों की ओर से किया गया कोई भी आक्रमण निरर्थक हो सकता है लेकिन पिछले 15 वर्षों में सोवियत नौसेना की शक्ति काफी बढ़ी है। जहाँ तक परमाणु क्षेत्र का सम्बन्ध है, अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता इतनी है कि सेना और अस्त्रों में कमी करने तथा इसी तरह की अन्य वार्ताओं में अपनी बात मनवाने की स्थिति में वह पहुँच गया है। नाटो सन्धि के सदस्य देश अपनी-अपनी विदेश-नीतियों में कुछ उदारता जरूर ला रहे हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों की अपेक्षा उन के रवैये को नरम कहा जाएगा लेकिन 1966 से नाटो सन्धि के सदस्य देशों में जो पराभवं चला रहा है उसे देखते हुए इस सन्धि के सदस्य देशों का रवैया पहले की अपेक्षा कुछ अधिक तत्न हो गया है। बताया जाता है कि नाटो सन्धि के सदस्य देशों ने सैनिक दृष्टि से अपने को आधुनिकतम बना दिया है। अभी से कुछ समय पहले तक अमेरिका और नाटो सन्धि के देशों के बीच सम्भार पराभवं नहीं होता था। लेकिन जिनेवा, हेलसिंकी और वेलघेड जैसे सम्मेलनों के बाद अमेरिका और नाटो सन्धि के देशों के बीच पराभवं होने लगा है और दोनों ही पक्ष इस पराभवं को बढ़ाने

गम्भीरतापूर्वक लेते हैं। उधर नाटो सन्धि के छोटे सदस्य देश भयभीत तरह समझ गए हैं कि यदि उन्होंने अपने आपको सन्धि से अलग कर लिया तो विश्व के घटना-चक्र को प्रभावित करने की अपनी क्षमता वे खो देंगे।

निस्सन्देह अस्त्र-शस्त्रों की होड़ से दोनों ही सन्धियों के सदस्य देशों को कोई लाभ पहुँचने वाला नहीं है। अपने अनुभवों से भी उन्होंने देखा लिया है कि अब तक किसी भी दृष्टि से वे इस प्रकार की होड़ से लाभान्वित नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों में से कोई भी पक्ष निःशस्त्रीकरण के बारे में सहस्र करके एक ठरफा फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की सैनिक क्षमता पर सन्देह रहता है और दोनों ही एक दूसरे से भयभीत रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्वेच्छा से अस्त्र-शस्त्रों में कमी करने और निःशस्त्रीकरण का कोई भी सक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन और वारसा सन्धि एक प्रकार से सदस्य देशों के स्थायी साधन बन गए हैं। इच्छा रहते हुए भी दोनों में से कोई भी पक्ष इन्हें भंग नहीं कर सकता पर समय आ गया है कि यदि निःशस्त्रीकरण और अस्त्र-शस्त्रों में कमी करने जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत को सफल बनाना है तो ये सन्धि संगठन समाप्त कर दिए जाने चाहिए।

यूरोपीय संसद्, जून 1979 एवं यूरोप के एकीकरण की ओर कदम

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से पश्चिमी यूरोप आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। उसका अन्तिम लक्ष्य यूरोप का राजनीतिक एकीकरण है। वह यूरोपीय संसद द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहता है। 17 मार्च, 1948 को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समुक्त रूप से कार्य करने के लिए ब्रुसेल्स में ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लक्जमबर्ग के विदेश मन्त्रियों ने 50 वर्ष की एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए थे। 20 दिसम्बर, 1950 को पश्चिमी देशों के रक्षा संगठन को उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन का रूप दे दिया था। फिर 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर, 1954 तक लन्दन में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग और ब्रिटेन तथा अमेरिका के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस सम्मेलन में ही तय किया गया कि पश्चिमी देशों के एकीकरण के लिए ब्रुसेल्स सन्धि में फंडरल जर्नेनी और इटली को भी शामिल कर लिया जाए। इस प्रकार यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई फिर 1948 में कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोप के नाम से एक सम्मेलन भी हुआ जिसमें बड़े-बड़े कोई 26 यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संसम्बली सहित एक समुक्त यूरोप के निर्माण का निश्चय किया। समुक्त यूरोप की दिशा में इस समय एक यूरोपीय संसद काम कर रही थी, जिसके दो सौ से अधिक सदस्य थे लेकिन इसके अभी कुछ सीमित अधिकार थे। जून, 1979 में प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा यूरोपीय संसद की विधिवत् स्थापना करके यूरोप के एकीकरण की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है।

यूरोपीय संसद का विवेचनात्मक विवरण 27 जून, 1979 के दैनिक हिन्दुस्तान में विशालाक्ष के एक लेख में दिया गया था, जो इस प्रकार है—

ग्राम चुनावों पर आधारित 410 सदस्यीय यूरोपीय संसद की स्थापना विश्व की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। इसे विश्व सरकार की ओर एक उन्मुखनीय कदम कहा जा सकता है। कम से कम कभी विश्व संसद बनी तो यूरोपीय मन्द उमरे लिए नमूने का काम देगी।

पर यहाँ यह भी मही है कि अभी यह संसद केवल बड़ी शक्तियों व एशियायी देशों के मध्य एक शक्ति बनने के लिए बनाई गई है। कुछ दशक पूर्व तक जहाँ रुम व अमेरिका विश्व पर एकछत्र राज्य कर रहे थे वहाँ पूर्ण विकसित और समर्थ, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि की अविकसित देशों की लूट का अगाध रूप से उपयोग करने में ममत्त थे। पर वापुंग सम्मेलन के बाद बने निर्गुट देशों के गुट या अफ्रीकी एकता संगठन व अरबराष्ट्रों के गुटों के अस्तित्व में अपने में उन यूरोपीय देशों के लिए यह सब सम्भव नहीं रहा है। फलतः मुद्रा-स्फीति, बेकारी व असन्तोष के चिह्न उनमें दिखाई देने लगे हैं। इन देशों के 80 लाख बेरोजगार युवक इनका प्रमाण हैं। यूरोपियन संसद का गठन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे राजनीतिक, आर्थिक व प्रभिरक्षा की दृष्टि से ये देश एकजुट होकर काम कर सकें एवं विश्व पर छाए रहने में सक्षम हों।

यूरोपीय संसद में अभी 9 देश शामिल हुए हैं—इंग्लैंड, फ्रांस, पं जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ग्रायरलैंड, डेनमार्क, हायलैंड तथा लक्जमबर्ग। ग्रीस भी अब इसका सदस्य बन रहा है। 7 जून को हुए इस संसद के ग्राम चुनाव में लगभग 20 करोड़ 18 वर्ष से ऊपर के मतदानार्थों में 410 सदस्य चुने गए हैं। उनमें 209 दक्षिणपंथी व तटस्थ दलों के हैं, 112 समाजवादी हैं, 44 साम्यवादी हैं, 23 हिगालवादी व शेप अन्य छोटे दलों के हैं, चुनाव में 53.2% लोगो ने मतदान किया। बेल्जियम व लक्जमबर्ग जहाँ मतदान अनिवार्य है, में 80% ने मतदान किया। शेप में इटली में 80% ने, पं जर्मनी में 66.5% ने, फ्रांस में 62% ने, इंग्लैंड में केवल 30% ने मतदान किया।

यूरोपीय संसद के प्रत्यक्ष चुनाव की परिवर्तना 22 वर्ष पूर्व 1956 में रोम की सन्धि में की गई थी पर इसका प्रारम्भ पं यूरोपीय देशों की संसदों के सदस्यों द्वारा 198 सदस्यों के चयन में हुआ। डिगॉन के पतन के बाद फ्रांस के नए गण्टुपति पोम्पिडू ने 1971 में ग्रीष्म के एक दिन विश्व के नज़रे पर हाथ रखते हुए कहा—देखो, कौसा छोटा यह यूरोप दीप्त रहा है फिर भी हमारे 30 करोड़ लोगो ने शत्रु 50 वर्षों में मानव का इतिहास बनाया है। हमारे पास क्षमताओं के विश्व का अद्वितीय भण्डार है। जहाँ तक आर्थिक शक्ति की बात है, यदि उत्तरी अमेरिका के बराबर नहीं तो भी हम से जो हमारी शक्ति बड़ी अधिक है। हमारे सामने जो ही विरुद्ध है कि हम या तो बड़ी शक्तियों के सामने झुक जायें या पं यूरोप के देशों को मिलाकर उसी सम्भावनाओं व क्षमताओं को

एकजुट करें। इन्हीं प्रयत्नों को मैंने पूरा करने का निश्चय किया है। यों पोम्पिडू ने पूर्व डिगॉल ने भी अटलांटिक से मूराल तक यूरोपीय शक्ति के निर्माण की बात कही थी। पर पोम्पिडू की बात अधिक व्यावहारिक थी। पोम्पिडू के साथ प. जर्मनी के चांसलर विलीब्राण्ट व ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री एडवर्ड हीथ भी थे। इस तरह पहली बार प. यूरोपीय एकता की नींव पड़ी। लक्जमबर्ग में इसका कार्यालय रखा गया पर पहले इस संसद के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए गए थे जबकि अब प्रत्यक्ष मत से चुने गए हैं। प. जर्मनी के विलीब्राण्ट इसके अध्यक्ष चुने गए।

अधिकार का अभाव

पर यहाँ प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि चुनी हुई संसद होने पर भी यह विश्व के लिए केवल दर्शनीय बनी रहेगी या एक प्रभावपूर्ण संसद बनकर यूरोप को एकीकृत जनतन्त्र की ओर ढालने में भी समर्थ होगी। अभी तक जो स्थिति है उसमें इसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह विश्व में अभी तक एकमात्र ऐसी संसद है, जिसको न कानून बनाने का अधिकार है और न ही सरकार बदलने का। यूरोपीय देशों का अभी तक सबसे प्रभावपूर्ण संगठन रोम की संधि के बाद बना, 13 सदस्यीय यूरोपीय इकॉनॉमिक कमिशन अर्थात् साम्राज्य बाजार आयोग है, जिसका गठन 1958 में किया गया था। यह यूरोपियन देशों के व्यापार का सम्मिलित रूप से नियन्त्रण करता है व यूरोपीय देशों के हित देखता है। यूरोपीय संसद को यह अधिकार जरूर दिया गया है कि इसका बजट रद्द कर दे, पर नया बजट बनाने का उसे अधिकार नहीं है। यूरोपीय साम्राज्य बाजार आयोग को भी चाहे तो रद्द कर सकती है, पर वो-निहाई बहुमत से ही लेकिन इतना बहुमत मिलना कभी भी इसके लिए सम्भव न होगा। फिर इस आयोग को पूर्ण रद्द करने का अधिकार है पर आयोग के किसी सदस्य को आयोग से हटाने का अधिकार नहीं है। यूरोपीय-साम्राज्य-बाजार के आयोग की परिषद् के कार्य में भी यूरोपीय संसद कोई बाधा नहीं डाल सकती है। केवल यह सुझाव दे सकती है। यूरोपीय इकॉनॉमिक कमिशन के 9 देशों के प्रधानमन्त्री व राष्ट्रपतियों की शिखर समिति पर इसका कोई दखल न होगा।

पुनः यूरोपीय आर्थिक आयोग के साथ ही उससे सम्बद्ध शक्तिशाली संस्थाएँ कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय, यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय व कृषि मूल्य एवं सहायक मूलतन्त्र हैं। इन संगठनों के हाथ में यूरोपीय संसद को विशेष अधिकार न दिए जाएँ व कम से कम बजट बनाने का अधिकार न दिया जाए, तब तक यह दिखावा ही रहेगा।

यूरोपीय संसद की एक समस्या इसके सदस्यों में आपसी मतभेदों के बने रहने का है। जहाँ चार बड़े राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, इटली व प. जर्मनी की इस संसद में 80-81 सीटें रखी गई हैं और शेष 5 छोटे राष्ट्रों की 25-25। चार बड़े-राष्ट्र इसका नेतृत्व पाने का यत्न कर रहे हैं। उनकी धारणाएँ भी अलग-अलग हैं। चुनाव अभियान में प. जर्मनी के चांसलर श्मिड ने इसके राष्ट्रीय संसदों से ऊपर उठाने व

यूरोपीय एकता बढ़ाने पर जोर दिया तो फ्रांस के राष्ट्रपति गिस्कार्ड ने इसे यूरोपीय जनमत का एक्कीकरण बताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती थंचर ने इसे साभा बाजार में सुधार के लिए उपयुक्त मच बनाने को कहा। इन सात भाषाओं से प्रकट है कि यूरोपीय ससद का सही विकास आसान बात नहीं होगी। सम्प्रति तो यह अमेरिका के सगठन का प्रतीकात्मक विकल्प य रूस-अमेरिका एव तृतीय विश्व के देशों के बीच शक्तिशाली आर्थिक कड़ी बनाने के प्रयास को ही प्रतिफलित करने पर केन्द्रित होगी। यूरोपीय ससद दो वर्षों में यूरोपीय मुद्रा चलाने पर भी विचार कर रही है।

दूरगामी महत्त्व

पर इस सबके बावजूद और स्थानीय स्वार्थों के होते हुए भी इस प्रयत्न के दूरगामी महत्त्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। यूरोपीय इकॉनॉमिक कमीशन के अध्यक्ष श्री जैन्किन्स के इस प्रत्यक्ष यूरोपीय जनतन्त्र का अभियान कहा है। सम्भव है कि विश्व जनतन्त्र के अभियान में भी ऐसे ही किसी पैटर्न से जन्म ले सकें।

यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन (नवम्बर 1980)

11 नवम्बर, 1980 को 35 देशों के सुरक्षा और सहयोग सम्बन्धी सम्मेलन (33 यूरोपीय तथा अमेरिका और कनाडा सहित) की स्पेन की राजधानी माड्रिड में शुरुआत सन्देश के माहोल में अधिक, सद्भावना के वातावरण में कम हुई। 1975 में फिनलैण्ड की राजधानी हेलसिंकी में पूर्व और पश्चिम में व्याप्त खाई कुछ पटी सी थी लेकिन समय सिरकने के साथ वह मृग-मरीचिका ही सिद्ध हुई और पूर्व और पश्चिम में व्याप्त खाई निरन्तर चौड़ी होती गई। माड्रिड सम्मेलन से यही लगा कि सद्भावना का अभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

माड्रिड सम्मेलन में सहयोग और सद्भावना के अभाव के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे हैं—

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर इतने अधिक रंग चढ़े-उतरे हैं कि छोटे देशों में जहाँ अधिक करीबी आई है बड़े देशों—विशेष कर अमेरिका और सोवियत संघ में दूरी बढ़ी है। हेलसिंकी सम्मेलन के फलस्वरूप आस्ट्रिया और हंगरी ने एक दूसरे देश के निवासियों के आने जाने के लिए वीसा व्यवस्था समाप्त कर दी लेकिन दो बड़े देशों में साहसिक बार्ता को लेकर गतिरोध तो बढ़ा ही अफगानिस्तान और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भी वे एक दूसरे को नहीं मुहाते। इस बीच पोलैण्ड में श्रमिकों की हड़ताल से कई पेचीदगियाँ उठ खड़ी हुईं। इन राजनीतिक मुद्दों को तूल देने हुए अमेरिकी प्रतिनिधि मैकम कॅम्पलमैन, अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति को विश्व शान्ति के लिए खतरा बताते हुए अपनी सैनिक शक्ति को भी सन्तुलित करने का संकेत दिया। उनके अनुसार सोवियत संघ युद्ध अस्त्रों पर अमेरिका में 150 अरब डॉलर अधिक खर्च कर रहा है जो कि उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 14 से 15% है जबकि अमेरिका केवल 4 से 5% ही खर्च करता है। कॅम्पलमैन ने कहा कि सोवियत संघ के पास इन समय अनिप्रायुनिक अस्त्रों की सूची में चार महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले तीन प्रक्षेपास्त्र, चार नए रिसम

की पनबुझियाँ तथा चार नए लड़ाकू बमबर्षक हैं। हेल्सिंकी सम्मेलन में अस्तो की रोक पर बल दिया गया था लेकिन सोवियत नेताओं और विशेष तौर पर राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेझ्नेव ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि माड्रीड सम्मेलन को 'सस्ते प्रचार का मंच न बनायें'। लगता है कि ब्रेझ्नेव की यह चेतावनी कारगर सिद्ध हुई क्योंकि पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने सन्तुलित खर्चा अपनाया। ब्रेझ्नेव ने नैटो को निरन्तर सशक्त बनाये जाने का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिमी देश पूर्व की आलोचना करते समय वस्तुस्थिति से भटक जाते हैं (इस बीच नैटो के अस्त्रागार में भी नए अस्त्र जुड़े हैं)।

इस सम्मेलन से लगा कि फ्रांस और पश्चिम जर्मनी सोवियत संघ को विश्व की सभी बुराइयों के लिए कठघरे में खड़ा करने के पक्ष में नहीं। फ्रांस के प्रतिनिधि ने तो माड्रीड सम्मेलन को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि वह पूर्व और पश्चिम में बिखराव का अनुभव कर रहा था। फ्रांस का मत था कि इस सम्मेलन के आयोजित होने से पूर्व और पश्चिम के सम्बन्धों में सुधार कम, बिगाड़ अधिक होगा लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन तथा कई नैटो देशों को स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। फ्रांस और पश्चिम का तर्क था कि बेशक अफगानिस्तान और मानवाधिकार का मुद्दा महत्वपूर्ण है लेकिन इस तथ्य को भी नहीं मुलाया जाना चाहिए कि पिछले पाँच वर्षों में पूर्व और पश्चिम में भाईचारे तथा आर्थिक सहयोग की जो इमारत पुख्ता हुई है उसमें दरारें पैदा करना किसी के लिए भी हितकर नहीं होगा। केवल पश्चिमी देशों में ही ऐसी भावना नहीं थी बल्कि रोमानिया जैसा देश भी आश्वस्त था कि ब्रेझ्नेव के सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धान्त दुरुपयोग के विरुद्ध उसे संरक्षण प्राप्त होगा।

माड्रीड सम्मेलन लगभग डेढ़ महीने चला। इसमें अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप की तीव्र आलोचना की गई। मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा सोवियत संघ पर प्रहार किए गए। कुल मिलाकर माड्रीड सम्मेलन की ठोस उपलब्धियाँ नकारात्मक रही।

आणविक शस्त्रों का प्रभाव (IMPACT OF NUCLEAR WEAPONS)

द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम चरण में अगस्त 1945 में मयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अणुबम गिराकर सम्पूर्ण विश्व को आणविक शस्त्रों की विनाशकारी शक्ति से दहला दिया। उस समय एक मात्र मयुक्त राज्य अमेरिका ही अणु शक्ति का स्वामी था। मोवियत रुम ने यह समझ लिया कि यदि आणविक अस्त्रों के क्षेत्र में अमेरिका ही एकाधिकार स्वामी रहा तो उनके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव को भविष्य में चुनौती देना असम्भव हो जायगा। अतः वह भी आणविक से अणुशक्ति का स्वामी बनने की चेष्टा करने लगा और शीघ्र ही उसने इस क्षेत्र में अमेरिका के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसके बाद तो आणविक अस्त्रास्त्रों के निर्माण की भारी होड़ लग गई। ब्रिटेन और फ्रांस भी अणु शक्ति के स्वामी बन गए। साम्यवादी चीन ने कुछ सोवियत सहायता के बल पर और बाद में अपने प्रयत्नों में आणविक शस्त्र-निर्माणकारी क्षमता प्राप्त कर ली। शान्तिपूर्ण रचनात्मक कार्यों के लिए भारत ने अणुशक्ति का विकास किया और मई, 1974 में पोवरण में पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट किया। इसे अनेक राष्ट्रों ने सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समझा जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अणुशक्ति का स्वामी होने हुए भी वह इसका सदैव शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करेगा। पाकिस्तान सैन्य उद्देश्यों के लिए तेजी से परमाणु बम के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आणविक शस्त्रों का प्रभाव (Impact of Nuclear Weapons)

आणविक शस्त्रों ने आरम्भ में ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उपलब्ध-पुनर्-मंचना शुरू कर दिया। इन्हीं के फलस्वरूप विश्व की दो महाशक्तियों के बीच पारम्परिक अविरतता की वृद्धि हुई जिसमें शीतयुद्ध (Cold War) का प्रयोगात्मक

मिला। आणविक शक्ति से सम्पन्न होने की लालसा ने शस्त्रीकरण की ऐसी विनाश-कारी प्रतियोगिता को जन्म दिया जो आज सम्पूर्ण मानव जाति के लिए वास्तव का डेर बनी हुई है। विश्व के राजनीतिज्ञ और सैन्य-विशारद इस बात से आतंकित हैं कि तृतीय महायुद्ध यदि छिड़ा तो अणु-आयुधों के प्रयोग के फलस्वरूप वह इतना विनाशकारी होगा कि युद्ध के बाद विजेता और विजित में कोई फर्क नहीं होगा। ज्ञान ही नहीं सम्पूर्ण मानव जाति का अधिकांश भाग नष्ट और विभिन्न गु-प्रभावों से ग्रस्त हो जाएगा।

आणविक शस्त्रों का प्रभाव शुरू से ही राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालने लगा और समय के साथ-साथ उसने विश्व की महाशक्तियों के लिए राजनीतिक प्रभाव और कूटनीति के नए द्वार खोल दिए। साम्यवादी जगत् में भी आणविक शस्त्रों ने संपर्क के तत्त्वों को प्रोत्साहित किया। एशिया और अफ्रीका के देश भी आणविक कूटनीतिक प्रभाव से न बच सके। विश्व के अनेक देशों की सैनिक दूर-रचना बदल गई। आणविक शस्त्रों के विपुल व्यय ने और इससे प्रभावित कूटनीति के नए पैतरी ने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर भी प्रभाव डाला।

इस प्रकार आणविक शस्त्र अपने जन्म से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के किसी न किसी रूप में आणविक शस्त्रों के प्रभाव से आक्रान्त हैं। स्पष्टता के लिए यह उपयुक्त होगा कि हम अणु-आयुधों के प्रभाव का पृथक्-पृथक् विवेचन करें—

1. आणविक शस्त्रों का सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि विश्व की दो महाशक्तियों-संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत रूस में कूट की जड़ें निरन्तर गहरी हो गईं। अमेरिका ने अणु-बम के आविष्कार को सोवियत रूस से सर्वथा गुप्त रखा जबकि ब्रिटेन और कनाडा को इस बात का पता था। जब अणु-बम का प्रयोग जापान पर किया गया तो उससे केवल हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं हुआ, अपितु रूस और पश्चिमी राष्ट्रों की युद्धवालीन मंत्री भी टूट गईं। स्टालिन ने अमेरिका द्वारा अणु-बम के रहस्य को रूस से गुप्त रखने की बात को गम्भीर विश्वासघात माना। उसे इस घटना से व्यक्तिगत रूप में भी बड़ा दुःख हुआ। रूस और अमेरिका में परस्पर तनाव उत्पन्न हो गया और दोनों ही देश एक दूसरे की शक्ति की दृष्टि से देखने लगे।

2. रूस अणु-शक्ति पर अमेरिका के एकाधिकार को अपने लिए और सम्पूर्ण साम्यवादी जगत् के लिए भारी खतरा मानने लगा अतः उसने अपनी सम्पूर्ण बुद्धि और सामर्थ्य अणु-बम के निर्माण में लगा दी। चार वर्षों के अल्पकाल में ही 1949 में उसने अणु-बम के रहस्य का पता लगा लिया। अब अमेरिका और रूस दोनों ही देश गुप्त रूप से वैज्ञानिक प्रसन्न-शस्त्रों के आविष्कार की होड़ में तान गए और दोनों ही राष्ट्र अणु-शक्ति की दृष्टि से अधिकधिक सम्पन्न होकर विश्व राजनीति को अपनी ओर मोड़ने के प्रयत्नों में जुट गए।

3 अणु-शक्ति जनित सन्देह और अविश्वास ने द्वितीय महायुद्ध के बाद शीत-युद्ध को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। सम्मेलनों और पारस्परिक विचार-विमर्श पर किसी न किसी रूप में आणविक शस्त्रों का प्रभाव छाया रहा। पश्चिमी देशों और रूस में समुक्तराष्ट्रसंघ के भीतर और बाहर अणु-शक्ति के नियन्त्रण व नियमन, निःशस्त्रीकरण, यूरोपीय सुरक्षा समस्या आदि पर तीव्र वाद-विवाद और बूटनीतिक संघर्ष चला जो आज भी यथापूर्व विभिन्न उतार-चढ़ावों के साथ जारी है। निःशस्त्रीकरण और शीतयुद्ध के क्षेत्र में आणविक शस्त्रास्त्रों का कितना प्रभाव रहा और आज भी इन क्षेत्रों में अणु-शक्ति अपना कितना आतंक जमाए हुए है, इसको 'शीतयुद्ध' और 'निःशस्त्रीकरण' के पिछले अध्यायों में दर्शाया जा चुका है।

4. अणु-शस्त्रों की प्रलयकारी शक्ति और अणु-युद्ध से मानव-सम्बन्धता के विनाश के भय ने सह-अस्तित्व की धारणा को आज पूर्वापेक्षा कहीं अधिक व्यावहारिक बना दिया है। विश्व की दोनों ही महाशक्तियाँ पारस्परिक सन्देह और अविश्वास के बावजूद यह भली प्रकार समझ चुकी है कि अणु-युद्ध में हार और जीत का कोई महत्त्व नहीं रहेगा क्योंकि विजेता भी उतना ही ध्वस्त हो जाएगा जितना अविजित देश। अतः अणु-युद्ध की निरर्थकता में सैद्धान्तिक रूप से विश्वास करते हुए दोनों ही देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथासम्भव ऐसा कठोर मार्ग ग्रहण करने से घबरेने की कोशिश करने लगे हैं जिससे व्यापक युद्ध भड़क उठने की सम्भावना न हो। सह-अस्तित्व के महत्त्व को आज विश्व के राष्ट्र पहले की अपेक्षा अधिक अच्युत तरह समझने लगे हैं। स्टालिन युग के बाद सोवियत विदेश-नीति भी इस प्रकार संचालित होने लगी है जिससे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की सम्भावनाएँ अधिक प्रबल हुई हैं। रूसी और पश्चिमी दोनों ही गुट यह मानने लगे हैं कि आज के अणु-युग में साम्यवाद व पूंजीवाद के सह-अस्तित्व का मार्ग ही विवेकपूर्ण है।

5 कोरिया, वूवा, वियतनाम, स्वेज आदि की घटनाएँ सिद्ध करती हैं कि आणविक अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग के भय ने महाशक्तियों को बिलकुल नियन्त्रित किया है। कोरियाई युद्ध में अमेरिका ने अणुधम का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि हम ना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो जाएगा और अणु-युद्ध का विस्फोट न केवल साम्यवादी वरन् पूंजीवादी गुट को भी नष्ट-भ्रष्ट कर देगा। अणु-युद्ध के भय ने ही कोरियाई युद्ध को स्थायी और सीमित क्षेत्रीय युद्ध के रूप में रखा। स्वेज काण्ड के समय ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल की सैनिक योजनाएँ इसीलिए विफल हुई कि रूस की ओर से आणविक प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग की धमकी दी गई। अणु-आयुधों के सम्भावित प्रयोग की चेतावनी मात्र ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में खलबली मचा दी और ब्रिटेन व फ्रांस को अपने बूटनीतिक व सैनिक मोर्चे बदल कर स्वेज से हट जाना पड़ा। इस प्रकार स्वेज का राष्ट्रीयकरण पूरा हुआ और अरब-राजनीति अरबों के पक्ष में मुड़ गई। ब्रिटेन को हट जाने से हुई रिकतता को भरने के लिए अमेरिका व रूस में होड़

शुरू हो गई और आज सगभग समूचा मध्यपूर्व इन दोनों महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में विभक्त है। इस कूटनीतिक अखाड़ेबाजी के कारण सम्पूर्ण मध्यपूर्व अशान्त बना हुआ है। क्यूबा प्रश्न पर भी आणविक आनुषो के प्रभाव ने अपनी पूरी छाप डाली। अमेरिका की बात मानने का कारण स्पष्ट करते हुए तत्कालीन सोवियत प्रधानमन्त्री क्लुशेव ने कहा कि यदि उस समय पूंजीवादी जगत् के साथ सघर्ष किया जाता तो पहले ही दिन सात करोड़ व्यक्ति नष्ट हो जाते। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने बलपूर्वक कहा कि इस प्रकार के महाविनाश के तथ्य से घ्रांख भूंदने वाले ही यह मूर्खतापूर्ण युक्ति दे सकते हैं कि युद्ध समाजवाद के प्रसार में सहायक होगा। साम्यवादी नेताओं ने घोषणा की कि समाजवाद का निर्माण अणुबमों के विस्फोट से विश्वव्यापी युद्ध का रूप धारण करने से बचा रहा।

6. आणविक-शक्ति सम्पन्नता के दल पर प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने की इच्छा ने ही साम्यवादी जगत् के दो महान् राष्ट्र रूस और चीन में मतभेदों व वैमनस्य की खाई को चौड़ा कर दिया। आज चीन साम्यवादी जगत् पर सोवियत नेतृत्व को चुनौती दे रहा है और रूस को पूरा भय है कि विशाल जनसंख्या वाला चीनी अजगर आणविक विष से उत्पन्न होकर निकट भविष्य में रूस के लिए एक भारी खतरा बन जाएगा। आणविक शक्ति के रूप में चीन के उदय ने और नेतृत्व व प्रभाव के चीनी मंसूवों ने द्वि-ध्रुवीयता (Bipolarity) के अन्त की दिशा में प्रभावकारी भूमिका अदा की है।

7. आणविक शस्त्रास्त्रों के प्रश्न ने अनेक एशियायी राष्ट्रों की विदेश और सामरिक नीति को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। विश्व की अणुशक्ति सम्पन्न शक्तियों का प्रयत्न और आप्रह है कि अणुशस्त्रविहीन राष्ट्र ऐसे शस्त्र बनाने का प्रयत्न न करें। वे चाहते हैं कि ये राष्ट्र परमाणु-शक्ति का विकास केवल असैनिक कार्यों के लिए करें। लेकिन विडम्बना यह है कि परमाणु अस्त्र-विहीन राष्ट्र पर परमाणु-अस्त्रधारी राष्ट्र के आक्रमण की सूरत में उनके बचाव की व्यवस्था का कोई ठोस आश्वासन या समाधान नहीं है। स्पष्ट है कि इस परिस्थिति ने परमाणु-अस्त्र-विहीन राष्ट्रों की शकाओं को बड़ा दिया है। इसीलिए कुछ राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और विदेश-नीति को इस तरह मोड़ देने को प्रयत्नशील हैं कि वे या तो स्वयं अणु-आयुधों का निर्माण कर सकें या ऐन-केन-प्रकारेण उन्हें प्राप्त कर सकें। भारत यद्यपि अणु-आयुधों का निर्माण न करने का निश्चय व्यक्त कर चुका है, तथापि उसने 1968 की परमाणु आयुध प्रसार प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है। अणुशक्ति सम्पन्न चीन के सम्भावित खतरे और पाकिस्तान-चीन के नापाक गठजोड़ को देखते हुए इस सम्भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत-सरकार अणु-आयुध न बनाने की अपनी नीति पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो सकती है। देशी और विदेशी पर्यवेक्षकों की धारणा है कि भारत के परमाणु अस्त्रों के विकास की समस्या पर नजिय रूप से सोचना शुरू कर दिया है और उसके लिए अधिक समय तक जनमत की उपेक्षा करना सम्भव नहीं होगा। मध्यपूर्व की

राजनीतिक व सामरिक व्यूह-रचना पर भी अणु-आयुधों की काली छाया पड़ रही है। इजरायल द्वारा अणुबम के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर होने की सूचनाएँ मिल रही हैं जिसका प्रभाव अरब राष्ट्रों की सैनिक व कूटनीतिक रणनीति पर पड़ना स्वाभाविक है। इजरायल की सैनिक शक्ति का भय कुछ अरब देशों को रूस के साथ गठबन्धन के लिए पहले ही से विवश किए हुए है और उसकी सम्भावित अणुशक्ति का भय यदि उन्हें सोवियत शिविर में पूरी तरह आ जाने को बाध्य करदे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पाकिस्तान परमाणु-बम निर्माण की दिशा में प्राण-पण से लगा हुआ है जो भारत के लिए चिन्ता का विषय है।

8 आणविक शस्त्रास्त्रों ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में असुरक्षा, अविश्वास, सन्देह और तनाव का वातावरण पैदा किया है जो नाटो, वारसा पैक्ट, आदि अनेक सैनिक संगठनों के उदय में सहायक हुआ है। एक-दूसरे पर आणविक आक्रमण के भय के फलस्वरूप सोवियत रूस और अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को जन्म दिया है। अपने-अपने पक्ष के देशों में अणु-आयुध सम्पन्न सैनिक केन्द्र स्थापित किए हैं। इससे उन देशों की आन्तरिक राजनीति और प्रभुसत्ता भी बड़ी सीमा तक प्रभावित हुई है। पराए देश में अपने आणविक केन्द्र स्थापित करने के लिए शक्तिशाली देशों ने उसको विशाल आर्थिक और सैनिक सहायता देकर अपना पिछलभू बनाने के सफल प्रयास किए हैं। उदाहरणस्वरूप, पाकिस्तान में अमेरिका नियन्त्रित गिलगित हवाई अड्डे की ओर इस आधार पर पाकिस्तान-अमेरिकी सम्बन्धों की कहानी दोहराना आवश्यक है।

सारांश यह है कि आणविक शस्त्रास्त्रों ने आधुनिक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक नीति को प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में कम या अधिक प्रभावित अवश्य किया है।

सम्भावित आणविक शक्तियाँ और प्रथम आणविक विस्फोटों की तिथियाँ

(Potential Atomic Powers and Dates of First Atomic Explosions)

यह देखना रोचक होगा कि विश्व में सम्भावित आणविक शक्तियाँ कौन-कौन-सी हैं अर्थात् जो राष्ट्र अणुशक्ति से सम्पन्न हैं उनके अतिरिक्त वे और कौन से राष्ट्र हैं जो अणु-शक्ति सम्पन्न बनने की ओर अग्रसर हैं या बनने की क्षमता रखते हैं। स्टीवेन रोजन तथा वाल्टर जोन्स ने मई 1974 में प्रकाशित अपने ग्रन्थ में सम्भावित आणविक शक्तियों को तीन समूहों में विभाजित कर उनकी सूची प्रस्तुत की है जो आगे दी जा रही है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भारत 18 मई, 1974 को अपने सफल भू-गर्भीय आणविक परीक्षण द्वारा देश का महत्वपूर्ण ऊँचा कर चुका है और 20 अप्रैल, 1974 को अपने प्रथम भू-उपग्रह 'मार्गभट्ट' को पृथ्वी में स्थापित कर पुनः अपनी महान् वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय दे चुका है।

सम्भावित आणविक शक्तियाँ
(Potential Atomic Powers)

ग्रुप I	ग्रुप II	ग्रुप III
बेल्जियम	आस्ट्रेलिया	अर्जेंटीना
कनाडा	आस्ट्रिया	ब्राजील
चेकोस्लोवाकिया	डेनमार्क	मैक्सिको
पश्चिमी जर्मनी	फिनलैण्ड	नार्वे
पूर्वी जर्मनी	हंगरी	स्पेन
भारत	नोदर्लैण्ड्स	दक्षिण अफ्रीका
इटली	पोलैण्ड	
जापान	यूगोस्लाविया	
स्विट्जरलैण्ड		

Source : Rosen & Jones : The Logic of International Relations, 1974, p. 178.

रोजन एव जोन्स ने प्रथम आणविक और ताप नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों की तिथियों की सूची भी दी है जो इस प्रकार है -

प्रथम आणविक और ताप-नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों की तिथियाँ
(Dates of First Atomic and Thermonuclear Test Explosions)

देश	प्रथम आणविक परीक्षण	प्रथम पुर्ण-स्तरी ताप-नाभिकीय परीक्षण	सत्रान्ति काल (वर्ष)
संयुक्तराज्य अमेरिका	जुलाई 16, 1945	नवम्बर 1, 1952	7.5
नोर्वेयत संध	अगस्त 29, 1949	अगस्त 12, 1953	4.0
ग्रेट-ब्रिटेन	अक्तूबर 3, 1952	मई 15, 1957	4.5
फ्रांस	फरवरी 13, 1960	अगस्त 24, 1968	8.5
चीन	अक्तूबर 16, 1964	जून 17, 1967	2.5

Source : Rosen & Jones : The Logic of International Relations, 1974, p. 169.

भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में और इसका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव
(India as a Nuclear Power and Its Impact on International Politics)

दगनादेश की धावावी मे सहायक बनकर भारत सरकार ने जिस तरह विश्व मे राष्ट्र वा मस्तक ऊँचा किया था उसी तरह भारतीय परमाणु वैज्ञानिको ने 18 मई, 1974 को सकल भूगर्भीय परीक्षण द्वारा देश का मस्तक एक बार फिर ऊँचा कर दिया । इस विस्फोट से भारत परमाणु-बिरादरी का छठा देश बन गया । भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यह विस्फोट शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही है और भारत शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही परमाणु-शक्ति का उपयोग करना चाहता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि परमाणु-शक्ति के रूप में भारत का उदय विश्व के अनेक राष्ट्रों को पसन्द नहीं आया, 'दबाव की राजनीति' मुखर हुई और कतिपय देशों में भारत के विरुद्ध गठबन्धन पुनः अधिक उग्र रूप में प्रकट होने लगा। "भारत के परमाणु-विस्फोट पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया अमेरिकी क्षेत्र में हुई। अमेरिका ने न केवल अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की, बल्कि यह भी कहा कि भारत के परमाणु-विस्फोट से विश्व में स्थायित्व को घाघात पहुँचेगा। अमेरिका की इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि वह नहीं चाहता कि कोई अन्य देश परमाणु-अस्त्र बनाए। अक्तूबर, 1964 में जब चीन ने पहला परमाणु-विस्फोट किया तब भी अमेरिका ने ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, यद्यपि उस समय अमेरिका और चीन के बीच इतना गम्भीर मतभेद था जितना भारत और अमेरिका के बीच कभी नहीं रहा।"

"एक बड़ी शक्ति का मुखर विरोध अकारण नहीं था। अमेरिका ने विश्व-स्थायित्व की ओट में विरोध किया। अमेरिका की दृष्टि में विश्व-स्थायित्व का तात्पर्य शायद उस शक्ति-सन्तुलन से है जो इस समय बड़ी शक्तियों के बीच विद्यमान है और वस्तुतः अमेरिका को इसी सन्तुलन के बिगड़ने की चिन्ता भी है। न्यूनाधिक यह चिन्ता सोवियत संघ की भी है। भारत परमाणु-अस्त्र न बनाने के अपने इरादे पर दृढ़ रहे, तो भी इस विस्फोट के बाद निकट भविष्य में सम्भावित विस्फोटों से भारत का रुतबा एक महाशक्ति जैसा बन जाएगा। इस तथ्य की नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता। 1971 में बंगलादेश के स्वाधीन होने पर एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत का रुतबा बढ़ा था, अब वह महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यह स्थिति किसी महाशक्ति को कैसे पसन्द आ सकती है?"

"अमेरिका के अलावा जिन अन्य दो देशों ने भारत के परमाणु-विस्फोट का मुखर विरोध किया वे थे कनाडा और जापान। कनाडा को शायद यह प्रच्छा नहीं लगा कि उसकी ही सहायता से परमाणु-भट्टी स्थापित करने वाला भारत उससे पहले परमाणु-शक्ति-सम्पन्न देश बन गया। जापान के विरोध का निजी कारण था। यह कारण लगभग वही था जो चीनी परमाणु-विस्फोटों के विरोध के समय जापान के सामने था। जापान जानता है कि क्षेत्रफल कम होने के कारण वह यदि चाहे तो भी बड़ी परमाणु-शक्ति नहीं बन सकेगा, किन्तु वह न केवल दक्षिण-पूर्वी एशिया की बल्कि विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और उसका भविष्य दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ बँधा है। वह इन देशों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लेने के लिए भरमक यत्न करता रहा है। पहले चीन ने और फिर भारत ने परमाणु-विस्फोट कर उसकी आर्थिक प्रमुखा को चुनौती दे डाली। जापान ने इन चुनौती को बड़ी गम्भीरता से लिया और वह अपनी परमाणु-नीति पर पुनर्विचार करने की सोचने लगा।"

"जापान ही नहीं, वे सभी देश ऐसा सोच सकते हैं जिनमें परमाणु-शक्ति बनाने की कम या अधिक क्षमता है। ऐसे देशों की संख्या आज 1972 में बड़ी अधिक है। पाने वाले समय में परमाणु-बम बनाने के लिए प्लूटोनियम पदार्थ बनाने में कम से

कम 19 और देश समग्र हो जाएंगे। ये देश हैं—ग्रास्ट्रेलिया, ग्रास्ट्रिया, ग्राह्वीतीना, बेल्जियम, बुरुगारिया, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिणी कोरिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान, रूमानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और ताइवान। इनके अलावा यूनान-नार्वे और हंगरी भी शीघ्र ही प्लूटोनियम बनाने लगेंगे। 1980 से मैक्सिको, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। इजरायल के पास अनुसन्धान के लिए जो परमाणु-भट्टियाँ हैं उनमें यदि वह चाहे तो पर्याप्त मात्रा में प्लूटोनियम तैयार कर सकता है।”

“लगभग 16 देश शायद ऐसे हैं जिन्हें 100 परमाणु-बम बनाने के लिए अपनी कुछ राष्ट्रीय आय का 1 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही देशों में भारत, इटली और जापान भी हैं क्योंकि इनके पास स्वदेशी यूरेनियम और पर्याप्त धन-क्षमता है। पश्चिमी जर्मनी की गणना भी इन देशों के साथ की जा सकती है; किन्तु उसके पास स्वदेशी यूरेनियम का भण्डार नहीं है। इनके अलावा 10 या 11 देश ऐसे हैं जो अपनी कुल राष्ट्रीय आय का 2 प्रतिशत तक खर्च करके परमाणु-अस्त्र सम्पन्न-देश बन सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका भी ऐसा ही एक देश है। उसके पास प्रचुर मात्रा में यूरेनियम और सुनियोजित धन-क्षमता है, किन्तु उसने यहाँ ईंधन-तत्त्वों के लिए पुनर्प्रक्रिया समर्थ नहीं है।”

ऐसी स्थिति में छोटे परमाणु-शक्ति-सम्पन्न देश के रूप में भारत के प्रादुर्भाव की विश्वव्यापी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। भारत सरकार ने अपनी ओर से बार-बार स्पष्ट शब्दों में यह घोषित किया कि भारत परमाणु-शक्ति के रचनात्मक उपयोग के पक्ष में है और वह इसी नीति का अनुसरण कर रहा है।

भारत की परमाणु-नीति

इस सन्दर्भ में भारत सरकार की परमाणु-नीति पर कुछ अधिक स्पष्ट विचार अपेक्षित है। भारत सरकार के वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ 1975 के अनुसार भारत की परमाणु-नीति के मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं—

भारत ने सफल भूमिगत परमाणु-परीक्षण की घोषणा करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग ने कहा कि यह उस कार्यक्रम का अंग है जिसका उद्देश्य परमाणु-प्रायोगिकी के क्षेत्र में, विशेषकर खनन और मिट्टी हटाने के कार्य में, परमाणु-शक्ति के उपयोग में भारत को अन्य देशों के समक्ष रखना है। भारत सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की कि भारत का परमाणु-हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है और वह परमाणु-विस्फोटों के सैनिक उपयोग के सख्त खिलाफ है।

न्यूजवीक को दिए गए इंटरव्यू में प्रधान मंत्री ने भारत की स्थिति को पुनः स्पष्ट किया। परमाणु टेक्नोलॉजी में सक्षम देश और परमाणु हथियार रखने वाले देश में अन्तर है, हमारा देश परमाणु हथियार वाला देश नहीं है, हमारे पास कोई परमाणु बम नहीं है। हमारा इरादा इस जानकारी या इस शक्ति की शान्तिपूर्ण कार्यों के अलावा अन्य किसी कार्य में इस्तेमाल का नहीं है। हमारे पड़ोसियों को

त्रिमी प्रकार का भय नहीं होता चाहिए। मच तो यह है कि हम इस परीक्षण को विज्ञान और टेक्नोलोजी में हो रही प्रगति के समकक्ष रहने के लिए किए जा रहे अपने अनुसन्धान कार्य का एक अंग मानते हैं। इसके लिए कोई नई बजट-व्यवस्था नहीं की गई। इस पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई और इसके लिए हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं थे।

भारत ने परमाणु-शस्त्र निषेध सन्धि 1968 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि यह सन्धि पक्षपातपूर्ण है। एक तरफ तो यह परमाणु-हथियारों वाले राष्ट्रों को इस बात की छूट देती है कि वे आणविक हथियारों का परीक्षण करते रहें और दूसरी ओर अन्य राष्ट्रों को इस बात की छूट नहीं देती कि वे शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भूमिगत परमाणु परीक्षण टेक्नोलोजी का विकास कर सकें। भारत ने वायुमण्डल में या समुद्र में परीक्षण नहीं किया क्योंकि इससे वातावरण बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है और आसपास के जनजीवन को खतरा भी हो जाता है, हालाँकि इस तरह के परीक्षण भारत दस वर्ष पहले भी कर सकता था।

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आरम्भ से ही दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं—ऊर्जा का उत्पादन और उद्योग चिकित्सा, कृषि-अनुसन्धान और अन्य क्षेत्रों में रेडियो ग्राइमेटोपी का उपयोग, और अपने आणविक प्रयत्नों के लिए कौशल, साज-सामान और तकनीक के मामले में आत्म-निर्भर हुआ जाए।

भारत के लिए परमाणु बम का प्रश्न देश की अस्मिता की रक्षा का प्रश्न है

पड़ोसी देशों के परमाणु-शक्ति-विकास ने भारत के लिए परमाणु-बम का निर्माण करना अनिवार्य बना दिया है—इस प्रकार का विचार भारत के अनेक राजनीतिक क्षेत्रों में पनप रहा है। मई 1981 के 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में हिमांशु जोशी ने "भारत के लिए परमाणु बम का प्रश्न देश की अस्मिता की रक्षा का प्रश्न है" नामक शीर्षक में जो विचार व्यक्त किए हैं वे परमाणु बम की अनिवार्यता के पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिमांशु जोशी का लेख इस प्रकार है—“यह बात लगभग तय है कि निजट भविष्य में पाकिस्तान त्रिमी भी क्षण परमाणु-बम का बिस्फोट कर सकता है। लोगों का अनुमान है कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे 64 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान की पठारियों में इसके लिए स्थान तय किया जा चुका है। इसके विपरीत कुछ अन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि राजस्थान की सीमा के निजट, पाकिस्तान के रेगिस्तान प्रदेश में भी सर्वेक्षण हो चुका है। पाकिस्तानी मैनियो द्वारा इधर अनेक गाँव तबाही करवाए जा रहे हैं। वहाँ के किसानों की माल भर पहले ही चेनाबनी दे दी गई थी कि वे अपनी फसल न बोएँ।

स्थान जो भी हो, पाकिस्तान का नैतिक-प्रशासन ही नहीं, वहाँ के वैज्ञानिक भी इसके लिए कटिबद्ध हैं कि जल्द-से जल्द बिस्फोट किया जाए। रीगन-प्रशासन का यन्दहस्तन जब में पाकिस्तान पर रहा है, दस उपमहाद्वीप की सारी स्थिति बदल

गई है। अमेरिका ने तब कर लिया है कि इस क्षेत्र विशेष में उसके हितों की रक्षा के लिए सुदृढ़, सशक्त पाकिस्तान का अस्तित्व अनिवार्य है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।

अमेरिका स्वयं ही पाकिस्तान को उदारतापूर्वक सैनिक-महायता नहीं दे रहा, बल्कि गुप्त रूप से जापान, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन से भी अनुरोध कर रहा है कि पाकिस्तान को आवश्यक अस्त्र-शस्त्र देने की व्यवस्था करें।

ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? यह प्रश्न सीमाओं की सुरक्षा का ही नहीं, देश की अखण्डता तथा अखिलता की रक्षा का भी है।

सकट जब सामने होता है, तभी हम चेतते हैं—हमारे साथ यही विडम्बना है! सन् 1947 से आज तक हमने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्न को पाकिस्तान की सैन्य-स्थिति की तुलना में ही देखने का प्रयास किया है। उस देश को हमने अपने समकक्ष माना जो जनसंख्या, क्षेत्रफल, आर्थिक-दृष्टि से हमसे कई गुना छोटा है।

भारत किन-किन राष्ट्रों से सैन्य सहायता ले रहा है, कौन-से हथियार बना रहा है—चीन ने कभी इसकी चिन्ता नहीं की। उसका लक्ष्य पहले शक्तिशाली अमेरिका रहा, और कालान्तर में मोवियन मंच। उसकी सारी सैनिक-तैयारियाँ इन्हीं राष्ट्रों की सैनिक-शक्तियों की सामने रखकर की गईं।

1962 में चीनी-आक्रमण के पश्चात् भी हमारे राष्ट्रीय चिन्तन में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। 1964 में चीन ने प्रथम परमाणु-बम का विस्फोट किया, कुछ वर्ष पश्चात् उद्‌जन बम का—तब भी हम मात्र सहम कर रह गए। भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से चीन ने अन्तर्ग महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र छोड़े, तब भी हम मूकदर्शक की तरह देखते रहे। हमारे राजनीतिज्ञों को सम्भवतः यही लगा कि इस दौड़ में चीन का मुकाबला कर पाना सम्भव नहीं, इसलिए सम्भावित हर खतरे को देख कर अनदेखा करते चले गए।

यदि पाकिस्तान ने पहल न की होती तो सम्भवतः अब भी हम सोए हुए ही रहते। चूंकि पाकिस्तान परमाणु-बम बना रहा है, इसलिए यहाँ भी तनिक हलचल महसूस होती है।

वास्तव में चीन के प्रथम परमाणु-बम विस्फोट के पश्चात् ही भारत को इस दिशा में अपने प्रयासों में तेजी लेनी चाहिए थी, किन्तु ऐसा कुछ हुआ नहीं।

18 मई, 1974 को षोकरण में 'परमाणु ऊर्जा आयोग' के वैज्ञानिकों की देख-रेख में भारत ने पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट किया था। इसका एकमात्र उद्देश्य शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही था। जिसे सत्तार के अनेक राष्ट्रों ने सैन्य-उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समझा और इसे बम-विस्फोट की संज्ञा दी।

विदेशी ही नहीं, स्वयं भारतीय भी इस भ्रम में रहे कि यद्यपि यह विस्फोट नहीं था, तब भी भारतीय वैज्ञानिक उस स्थिति तक पहुँच चुके हैं कि जब चाहे परमाणु-बम का निर्माण कर सकते हैं।

पोकरण की सफलता के पश्चात् जिस द्रुतगति से अनुसन्धान का कार्य चलना चाहिए था, सरकार की नीति की शिथिलता से चल नहीं पाया। मोरारजी के प्रशासन-काल में तो घोर उपेक्षा की नीति रही। यहाँ तक कि श्रीमती गाँधी के पुनः सत्ता में आने के कुछ महीने पश्चात् तक भी वस्तुस्थिति में अधिक अन्तर नहीं आया।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि परमाणविक-अनुसन्धान के क्षेत्र में 20% भी लक्ष्यों की प्राप्ति अब तक नहीं की जा सकी है। यूरेनियम-235 के परिष्कार के लिए जिस गति से कार्य होना चाहिए था, हुआ नहीं। आरम्भ में चीन भारत से इस क्षेत्र में 5-6 साल पीछे था, किन्तु अब स्थिति वैसी नहीं है। परमाणविक-खोजों के कुछ क्षेत्रों में तो वह भारत से बहुत आगे निकल गया है। पाकिस्तान भी दो-तीन सालों में हमारे समकक्ष आ जाए तो आश्चर्य नहीं।

यह सोचना बड़ा भ्रामक है कि यदि हमने परमाणु-बम का विस्फोट किया तो बड़े राष्ट्र हमारे विरुद्ध हो जाएँगे और छोटे राष्ट्र सन्देश की दृष्टि से देखेंगे। चीन ने इतने सारे परमाणु तथा उद्‌जन बमों का विस्फोट किया और आज भी खुलेआम वायु-मण्डल में विस्फोट कर रहा है, दुनिया में ऐसा कौन-सा देश है, जो उसका विरोध कर रहा है ?

शक्ति की पूजा सर्वत्र होती है, इस प्रश्न पर दो मत नहीं हो सकते किन्तु प्रश्न यह है कि हम क्यों शक्ति अर्जित करने से घबरा रहे हैं ? तकनीकी ज्ञान की हमें कमी नहीं, साधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं, फिर इस दिशा में जिस गति से कार्य होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पा रहा है ?

तागपुर परमाणु-विद्युत गृह के लिए अमेरिका से प्राप्त प्रयुक्त यूरेनियम से ही हम 200 बम आसानी से बना सकते हैं।

यूरेनियम हमारे पास है। इसके साथ-साथ थोरियम की भी कमी नहीं। अनुमान है कि 350 हजार टन थोरियम ऑक्साइड हमारे पास उपलब्ध है। थोरियम को यूरेनियम में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस ओर यथासमय ध्यान दिया गया होता तो अब तक यह कार्य भी पूरा हो चुका होता। दलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जिम गति से कार्य चल रहा है, उसे पूरा होने में अभी समय लगेगा।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत थोड़े-से प्रयास में परमाणु बम बना सकता है और लगभग दो साल के थम के पश्चात् उद्‌जन-बम का विस्फोट करने में भी सफल हो सकता है।

परमाणु की राजनीति

परमाणु शक्ति का विवास राजनीतिक विस्तारवाद के उद्देश्य से पूरी तरह प्रभावित है। महाशक्तियाँ जिस प्रकार परमाणु की राजनीति में लिप्त हैं इस पर नवम्बर, 1981 के दिनमान का अग्रनिविष्ट सम्पादकीय लेख अच्छा प्रमाण मानता है—

“1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु नरमेश किया था तब उसका मूल कारण शत्रु भय नहीं, बल्कि विजय और अन्वेषण का दर्प तथा प्रहकार था। तब रूस या किसी और के पास परमाणु शक्ति थी ही नहीं और अब जब वह न्यूट्रोन बम बनाने या यूरोप में नए परमाणुवाहक प्रक्षेपास्त्र लगाने की तैयारी कर रहा है तब भी उसके मूल में अपनी पराजय का भय उतना नहीं है जितना कि लागडाट और हथियारों की राजनीति के जरिये यूरोप से जुड़े और उसे जोड़े रहने तथा दूसरों को भयभीत किए रहने की लालसा है।”

यह सही है कि जब से रूस के पास इतने परमाणु हथियार हो गए हैं कि वह भी यूरोप और अमेरिका को ध्वस्त कर सके, तब से इस बात का महत्व पट गया है अमेरिका में सम्पूर्ण दुनिया को साढ़े तीन बार ध्वस्त करने की शक्ति है। तर्क की दृष्टि से अस्त्र-शस्त्र सग्रह की होड़ के पीछे किसी न किसी तरह का भय होता ही है—चाहे वह युद्ध में पराजित होने का भय हो या नेतृत्व कायम न रख पाने का, फिर जब दो देशों के पास एक दूसरे को नष्ट करने लायक ताकत जमा हो जाए और इसके खटको पर पन्नों द्वारा ही नियन्त्रण सम्भव हो तो स्थिति और भी नाजुक हो जाती है—बया पना किसी जानी अनजानी तकनीकी गलती के कारण कहीं कोई स्वनालित यन्त्र चालू न हो जाए। यह एक बात है, लेकिन बतौर शक्ति प्रदर्शन के यूरोप के वायुमण्डल में नियन्त्रित परमाणु विस्फोट कराने की धमकी देकर सबके मन में घातक पैदा करना दूसरी बात है, जैसा कि अमेरिका के विदेशमन्त्री अलेक्जेंडर हेग ने हात में किया था। हेग के बयान का अमेरिका में भी विरोध हुआ, लेकिन यह कहना कि रूस को गैर-परमाणु अस्त्रों से यूरोप पर हमला करने में रोकने के लिए ऐसा किया जा सकता है, स्पष्ट कर देता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में धौंसपट्टी का स्थान बरकरार है।

यूरोप में अस्त्र परीमीमन के लिए जिनेवा में 30 नवम्बर, 1981 में बैठक शुरू हुई जिसमें अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देश और रूस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। असल मुद्दा था कि सोवियत संघ क्या करे कि नैटो देशों में वे नए प्रक्षेपास्त्र न लगाए जाएँ, जिनके बारे में 1979 में फैसला किया गया था। बैठक बिना किसी निश्चिन्त वार्ता के समाप्त हो गयी और दूसरी बैठक मार्च, 1982 में करना तय किया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन का कहना है कि जिस अवधि में नैटो देशों ने 1,000 परमाणु बम घटाए उमी अवधि में सोवियत संघ ने एस एस.—20 क्रिसम के उन्नत प्रक्षेपास्त्र स्थापित किए हैं जो 750 परमाणु बम फेंक सकते हैं। ये प्रक्षेपास्त्र एक साथ तीन बग अलग-अलग दिशाओं में भेज सकते हैं। इनका परास 5,000 किलोमीटर है और ये पश्चिमी रूस में हैं। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह से जाया जा सकता है। रूस के पास एस एस.—4 और एस. एस.—5 क्रिसम के भी 350 मध्य परास प्रक्षेपास्त्र हैं, लेकिन 1977 तक पश्चिमी यूरोप के अनेक हिस्से इनकी मार में नहीं आते थे।

रूसी खतरे की काट के लिए 1979 में तय पाया गया कि पश्चिम-2 और कूजर प्रक्षेपास्त्र नौटो देशों में स्थापित किए जाएं। 108 पश्चिम पश्चिम जर्मनी में लगने हैं और 464 कूजर प्रक्षेपास्त्र इन देशों में—ब्रिटेन में 160, डट्नी में 112, पश्चिमी जर्मनी में 97, बेल्जियम में 48 और हॉलैंड में 48। यह कार्य 1983 के उत्तरार्द्ध में शुरू होता है।

पश्चिम प्रक्षेपास्त्रों की मात्रा दायरा 1600 किलोमीटर है और कूजर की 2,400 किलोमीटर तक है। इनके मुंह मामूली तथा अन्य रूसी शहृं के की ओर होंगे।

अमेरिका की चिन्ता यह है कि सोवियत संघ यूरोप और एशिया महाद्वीप के विशाल भू-भाग का यूरोप से लगा हिस्सा है, इसलिए उसकी समूची मंहारक शक्ति रूस में ही केन्द्रित है, जिसके चलते वह जब चाहे तब पश्चिम यूरोप को दबोच सकता है। मैनिव सन्धि (नौटो) तथा रक्त, ससृति और विचारधारा में अमेरिका और पश्चिम यूरोप एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, इसलिए पश्चिम के मन में रूस का डर जहें जमाए हुए है, लेकिन इन भय के कारण पश्चिमी यूरोप को परमाणु घस्रों का अग्राहा बना देने में युद्ध का खतरा बढ़ता ही है, घटना नहीं, इसीलिए यूरोप में वहे पैमाने पर परमाणु प्रसार विरोधी जलूम भी निकले।

30 नवम्बर, 1981 में जिम वार्ता की शुरुआत हुई है वह एक नई सोदेवाजी का आरम्भ है जिसका अन्त अनिश्चित है। रीगन के इस वाक्य का क्या अर्थ लगाया जाए कि यदि सोवियत संघ अपने प्रक्षेपास्त्र यूराल पर्वत के पूर्व में ले जाने की रात्री हो जाए तो भी विरोध फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूसी प्रक्षेपास्त्र बहुत जल्द स्थानान्तरित किए जा सकते हैं।

पश्चिमी यूरोप की अमली चिन्ता है कि मान लीजिए कभी रूस ने पारम्परिक घस्रों में यूरोप पर हमला किया, तो हो सकता है कि अमेरिका अपनी भूमि से जवाबी हमले में परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का विरोध न करे। इसलिए क्योंकि पश्चिम-2 और प्रक्षेपास्त्र अमन्यित किए जाएं, मगर ऐसा करना भी खतरे में खाली नहीं है।

“यदि यूरोप के देश और रूस दोनों चाहें तो वे एक ऐसी सर्वसम्मत व्यवस्था कर सकते हैं कि परस्पर भय या आतंरिक युद्ध की सम्भावना कम से कम यूरोप में परमाणु-विनाश का भय न रहे जाए, यह पूरी तरह तभी सम्भव हो सकता है, जब सभी देश शक्ति सन्तुलन की राजनीति छोड़ दें, करना निर्क यूरोप के देशों में किए गए सभी सम्भौत क्षेत्रीय और अल्पकालिक हो हींगे और युद्ध की विभीतिका से या उसके परिणामों से यूरोप की नहीं बचाया जा सकेगा।”

परमाणु अस्त्रविहीन क्षेत्र आवश्यक

परमाणु-शक्ति का विकास त्रिम ढग से विध्वनात्मक दिना में बढ़ता जा रहा है और नए राष्ट्र परमाणु-शक्ति बनने का स्वप्न मैखीने लगे हैं, उमें देखते हुए विश्व के कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में इस विचार पर बल दिया जाने लगा है कि अब समय पा गया है जब महानक्तियों को और बड़े देशों को परमाणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण

प्रयोग की बात गम्भीरतापूर्वक सोचनी चाहिए। भारत द्वारा मई 1974 के परमाणु-परीक्षण ने जिन अनेक प्रश्नों को उभारा, उनमें से एक मुख्य प्रश्न 'अणु-शक्ति केवल शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिए' का है जिस पर भारत प्रारम्भ से बल देता आ रहा है। एक दूसरा विचार 'परमाणु अस्त्रविहीन क्षेत्र' का है।

उपर्युक्त सन्दर्भों में हम एक तो जापान के प्रसिद्ध दैनिक 'असाही ईवनिंग न्यूज' के सम्पादकीय का और दूसरे मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में मुस्लिम देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव का उल्लेख करना चाहेंगे¹—

जापानी दैनिक 'असाही ईवनिंग न्यूज' के सम्पादकीय में उल्लेख था कि "भारत के परमाणु-परीक्षण के बाद से विकसित देश परमाणु-शक्ति के नए प्रयोगों और इससे विजयी प्राप्त करने की व्यापक योजना के बारे में सोचने लगे हैं। जापान समझता है कि विकासशील देशों में परमाणु-अस्त्रों के निर्माण की प्रगति को रोकने से लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। यह एक लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए सभी देशों को मिलजुल कर प्रयत्न करना है। विकसित अथवा विकासशील सभी देशों का कर्तव्य है कि जो देश अपने यहाँ परमाणु-शक्ति का विकास करें वे उसका उपयोग निश्चित रूप से शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय तो यह है कि परमाणु-अस्त्रों का प्रसार रोकने की सन्धि को मजबूत बनाया जाए। जिन देशों में इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं या हस्ताक्षर के बाद जिन देशों की सरकारों ने इसकी पुष्टि नहीं की है उन्हें तुरन्त ही ऐसा करने के लिए कहा जाना चाहिए। हान ही में अमेरिका ने मिस्र और इजरायल दोनों को ही परमाणु-शक्ति सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने का वायदा किया है। लेकिन बड़े देशों को इसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि जिन देशों को परमाणु-शक्ति सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, वे परमाणु अस्त्रों का प्रसार रोकने वाली सन्धि पर हस्ताक्षर जरूर कर दें।"

मलेशियायी राजधानी कुआलालम्पुर में मुस्लिम देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया—

"हम सभी परमाणु-शक्ति-सम्पन्न देशों से यह आश्वासन चाहते हैं कि विकासशील देशों के विरुद्ध कभी भी न तो परमाणु-अस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा और न उन्हें इस तरह की कोई धमकी दी जाएगी। परमाणु-अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध एक महत्वपूर्ण और तात्कालिक प्रश्न है। निःसन्देह सभी तरह के परमाणु-परीक्षणों पर रोक लगाना और देशों को परमाणु-अस्त्र बनाने से रोकना भी एक ऐसा मामला है जिस पर सर्व प्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए।"

"हम समझते हैं कि परमाणु-अस्त्रविहीन क्षेत्रों का निर्माण बहुत ज़रूरी है।

इस प्रसंग में हम ईरान के इस सुभाव की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि पहला परमाणु-अस्त्रविहीन क्षेत्र पश्चिमी एशिया बनाया जाए। हमारी राय में संयुक्तराष्ट्र महासभा में इस सुभाव पर विचार होना चाहिए। परमाणु-अस्त्र तैयार करने की इच्छा रखने वाले देशों की संख्या में तेजी से कमी होनी चाहिए। परमाणु-अस्त्रविहीन क्षेत्रों की स्थापना के लिए इस समय पहला कदम यही हो सकता है कि परमाणु-अस्त्र रखने वाले देश या परमाणु-अस्त्रों का मग्न करने वाले देश सन्धि द्वारा बचन दें कि वे न तो अब आगे परमाणु-अस्त्रों का निर्माण करेंगे और संग्रहीत-अस्त्रों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्रमध्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। माय हो यह भी आवश्यक है कि परमाणु-अस्त्रों वाले देश सन्धि की उस धारा की सरकारी तौर पर पुष्टि करें जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि वे कभी भी न तो परमाणु-अस्त्रों का प्रयोग करेंगे और न ही इस तरह की कोई धमकी देंगे।”

“परमाणु-अस्त्रों वाले कुछ देशों ने परस्पर ऐसी सन्धियाँ जल्द की हैं जिनमें उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध कभी भी परमाणु-अस्त्र प्रयुक्त न करने का बचन दे रखा है लेकिन अब इस प्रकार की सन्धि के क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। पश्चिमी एशिया में परमाणु-अस्त्रविहीन क्षेत्र बनाने के सुभाव को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। संयुक्तराष्ट्र महासभा में इस सुभाव को स्पष्ट किया जाना चाहिए। पश्चिमी एशिया के अलावा अन्य स्थानों में भी परमाणु-अस्त्रविहीन क्षेत्रों की स्थापना की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका, दक्षिण-पूर्वी एशिया और जापान सहित पूर्वोत्तर एशिया में इस प्रकार के क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है।”

“परमाणु टेक्नोलॉजी के विकास के साथ-साथ परमाणु-अस्त्रों के प्रसार की सम्भावनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। इसमें मसूचे विश्व में अग्रता और अस्थिरता का बनावरण ही बनेगा, इसलिए आवश्यक है कि अनेक दिशाओं में अनेक स्तरों पर उपाय किए जाने चाहिए। जब तक संयुक्त रूप में इस प्रकार के प्रयत्न नहीं किए जाएंगे, परमाणु-अस्त्र-प्रसार-सन्धि हस्ताक्षर हो जाने के बाद भी कारगर निड नहीं होगी। परमाणु-अस्त्रों के बारे में वर्तमान स्थिति काफी चिन्ताजनक है। परमाणु-अस्त्रों के प्रसार और उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए यही उपयुक्त समय है और यदि तत्काल ही इस दिशा में कुछ नहीं किया गया तो भविष्य में स्थिति जटिल हो जाएगी और फिर परमाणु-शक्ति सम्पन्न बड़े देश चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगे।”

यथा अणु-अस्त्रों के बल पर हो अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता-राजनीति में स्थान सम्भव है ?

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में अमोमिष्ट प्रोफेसर बीनविदर्या गोविन्द पुरोहित देशपाण्डे ने मापतादिक दिनमान में अपने एक विद्वत्तापूर्ण लेख में इस बात का मूल्यनिर्णय किया है कि क्या केवल अणु-अस्त्रों के बल पर ही

अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता-राजनीति में स्थान पाना सम्भव है। श्री देशपाण्डे ने लिखा है एक विचार यह है कि चीन ने आणविक अस्त्रों का निर्माण करना शुरू किया और उन अणु-अस्त्रों के बल पर ही चीन को अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता-राजनीति में अपना स्थान मिला। पहली नजर में चाहे यह तर्क कितना ही ठीक दिखाई दे, लेकिन गहराई से सोचने से यह मगन नहीं लगता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन भी आणविक राष्ट्र है, परन्तु अणु-अस्त्रों के निर्माण से क्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका स्तर कुछ बढ़ा है? सत्य तो यह है कि अणु-अस्त्रों का निर्माण भी द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद में ब्रिटेन की निरन्तर घटती प्रतिष्ठा को बचा नहीं सका। अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता-राजनीति की बात तो जाने दीजिए, यूरोप में, और वह भी पश्चिमी यूरोप में ही, ब्रिटेन दूसरे दर्जे का राष्ट्र बन कर रह गया है। इस विरती प्रतिष्ठा को मुबारने के लिए और जिनानी अश्वभावस्था को जीवनदान देकर ऊपर उठाने के लिए आज ब्रिटेन को यूरोप में जाना पड़ रहा है।

इसके विपरीत जापान को लीजिए। जापान के पास आणविक अस्त्र नहीं है और उसका मर्यादकरण भी मत कुछ वर्षों में ही शुरू हुआ है। इस पर भी दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्थिति के मन्दमं में जापान की शक्ति को नजरदाज नहीं किया जा सकता। द पू एशिया में चीन की भूमिका के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, परन्तु यह मदा भूल जाते हैं कि द पू एशिया में जापान सबसे आगे है। सत्ता-केन्द्रों में वह कभी का स्थान पा चुका है इसलिए महाशक्ति होना और अणु-अस्त्रों का निर्माण करना दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं माने जा सकते। इन्हीं अर्थ यह नहीं कि अणु-अस्त्रों का निर्माण न किया जाए या कि जापान भविष्य में उनका निर्माण करेगा ही नहीं। तात्पर्य यह है कि अगर कोई राष्ट्र महाशक्ति है तो अणु-अस्त्रों का निर्माण उसकी महत्ता को और बढ़ा सकता है; पर ऐसा नहीं कि अणु-अस्त्र बनाने वाले राष्ट्र स्वतः महाशक्ति बन जाते हैं। हाँ, बड़ी शक्तियों के पास अणु-अस्त्र हो सकते हैं। कल यदि हम अणु-अस्त्र तैयार कर लें तो हिन्दुस्तान एकदम महाशक्तियों में स्थान पाएगा, ऐसा नहीं है। सम्भावना यही है कि पहले बम-विस्फोट के बाद थोड़ा दबदबा बढ़ेगा पर जल्द ही महानता का वह बुलबुला फूट भी जाएगा।

श्री देशपाण्डे के इस मूल्यांकन में हम इन शब्दों को जोड़ना चाहेंगे कि—“परन्तु यदि भारत अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय शक्ति के लिए आवश्यक तत्त्वों का प्रभूत विकास कर लेता है, सबल प्रतिक्षात्मक शक्ति से सम्पन्न होने के साथ ही अपनी आक्रामक शक्ति भी जुटा लेता है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र भारत पर हमला करने के पूर्व उसी प्रकार सोचे जिन प्रकार अमेरिका रूस पर या रूस अमेरिका पर हमला करने से पहले सोचेगा, महान् आर्थिक और तकनीकी विकास द्वारा भारत की जनता सुन्नी और सम्पन्न बन जानी है, तो महानता का वह बुलबुला फूटेगा नहीं बल्कि चिरस्थायी होकर उसी प्रकार भारत के गौरव को पुनर्जीवित करेगा जिन

प्रकार कि अनीत में भारत का गौरव था जबकि वह 'विश्व-गुरु' जैसी उपाधियों से विभूषित था।"

अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा आज और कल

जब शस्त्रों का ताण्डव नृत्य हो रहा है, राष्ट्रों के सैनिक शिविर नित नए अस्त्र-शस्त्रों से सजाए जा रहे हैं और फलस्वरूप विश्वयुद्ध के विस्फोट की आशंका से मानव-जाति त्रस्त है तो वर्तमान और भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न सर्वोपरि है। इस सम्बन्ध में सोवियत संघ के प्रो जी प्रोएक्टोर ने अप्रैल, 1978 की सोवियत भूमि में जो विवेचनात्मक प्रकाश डाला है वह पढ़ने योग्य है—

“आधुनिक विश्व में जिसमें गहन सामाजिक और क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, सभी राष्ट्रों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक मान रास्ता नमनीय ढंग से वर्गीय, राष्ट्रीय और सामान्य मानवीय हितों को सम्बद्ध करने के बहुपक्षीय प्रयासों के जरिए है। वास्तविक व्यवहार में साम्राज्यवादियों की वर्तमान नीतियाँ इन प्रयासों की सफलता की राह में अनेकानेक बाधाएँ खड़ी कर रही हैं।

पश्चिमी देशों की वर्तमान वैदेशिक नीति अन्तर्विरोधों का जाल है जो स्वयं अपने में अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के ध्येय के लिए कई कठिनाइयाँ और खतरे पैदा करता है।

नाभिकीय अस्त्र-विनाश की रोकने की सामान्य प्रवृत्ति और दानवीय युद्ध मशीन के कार्यकलाप में जो स्वतः पुनरुत्पादन के अन्तर्निहित तर्क द्वारा गतिशील होकर विश्व को निरन्तर विनाश के कगार की ओर धकेलती रहती है, भारी अन्तर है और इसके कारण पूरी तरह स्पष्ट हैं। अन्ततः समाजवादी व्यवस्था के देशों के साथ शान्ति के लिए शक्ति सन्तुलन कायम रखने की घोषित नीति और सामूहिक सहाय के नए से नए हथियारों का निर्माण कर स्थिरता के इस बहुप्रचारित कारक को उलटने के पश्चिम के प्रयासों के बीच स्पष्ट अन्तर्विरोध है।

यदि हम केवल कुछ ही सैनिक विपत्तियों का उल्लेख करें तो इस सदी के दौरान मानवजाति पर थोपे गए दो विश्व युद्ध और उसके बाद शीत-युद्ध, वियतनाम पर आक्रमण एवं मध्यपूर्व का मकट आदि सभी ने एक ही बात मिट्टी की है, वह यह कि क्रमोच्च साम्राज्यवादी आक्रमणकारी जिन्होंने युद्ध शुरू किए, अपने एक भी उद्देश्य को मिट्टी नहीं कर सके बल्कि उन्होंने जो पाया वह उनकी इच्छा के विपरीत था। विजयी महान् अक्रूर समाजवादी शान्ति के बाद से साम्राज्यवादी आक्रमण के लिए सम्भावनाएँ लगातार घटती रही हैं।

अपने युग के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक सम्बन्धों के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों के विश्लेषण के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाजवादी देश यह मानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने का मुख्य साधन भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों का शान्तिपूर्ण सहजीवन है।

सोवियत संघ जिस शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति का अनुसरण करती है, उसके अर्थ की विवृत करने हुए पूँजीवादी प्रचार निरन्तर 'सोवियत खतरे' की बात करता है, परन्तु सोवियत संघ के पास एक प्रमुख आधुनिक राज्य के नाते

उतनी ही सैनिक क्षमता है जो उसकी महत्ता के अनुरूप होनी चाहिए जिससे वे अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को आवश्यक स्तर पर रख सकें। समाजवादी जगत् अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की सम्भावनाओं के प्रति आशावान है।

समाजवादी देशों का यह विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति और शान्ति की समस्याओं के प्रति भिन्न व्यवस्थाओं वाले राज्यों के दृष्टिकोण में भाज अधिक से अधिक समान आधार है। नीति के तत्त्वों को विक्रमित करते रहना आवश्यक है जो जनगण को एक दूसरे के निकटतर लाने हैं न कि उन्हें जो उनमें यह फूट डालते हैं।

जैसा कि यूरोपीय शान्ति और सुरक्षा सम्मेलन के अन्तिम सम्पादक ने मम के रूप में निर्धारित किया गया था, वार्ता को अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के आदर्श की सर्वाधिक पूर्ण की दिशा में सतत प्रगति के साथ शान्ति की दीर्घकालिक योजना पर केन्द्रित होना चाहिए। जहाँ तक यूरोप की परिस्थिति का सम्बन्ध है तो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव, सोवियत मंच की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष मण्डल के अध्यक्ष लियोनिद् ब्रेझ्नेव ने अक्टूबर 1977 में भारत के प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई की सोवियत सभ की यात्रा के दौरान ठोस कार्यवाहियों का जो कार्यक्रम अमल में लाने के लिए प्रस्तुत किया था, वह राजनीतिक तनाव-रहित्व की दशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इस कार्यक्रम में हेल्सिंकी सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राज्यों के लिए खास तौर से एक ऐसी सन्धि सम्पन्न करने की बात शामिल है जिसके अनुसार वे एक-दूसरे के विरुद्ध सबसे पहले नाभिकीय शस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे और कम से कम ऐसा समझना करेंगे कि वे सैनिक राजनीतिक दलबन्दी और गठबन्धन का विस्तार नहीं करेंगे और पारस्परिक विश्वास निर्मित करने के लिए कदम उठाएँगे। लियोनिद् ब्रेझ्नेव ने श्रेमलिन में अक्टूबर अन्ति की 60वीं जयन्ती के उपलक्ष में आयोजित समारोह में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में जो सुभाव दिए थे, उनकी पूर्ति में हथियारों की होड़ सीमित करने की दिशा में एक विराट कदम उठाया जा सकता है।

समाजवादी देशों द्वारा अनुमानित शान्ति की सुनगम नीति, पश्चिमी सरकारों की बंदेजिक नीति की दिशा के मथार्थपरक पक्ष, गुट-निरपेक्ष देशों का बढ़ता हुआ प्रभाव और प्रगतिशील जनता की शक्तिशाली आवाज—ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं तथा शान्ति की दिशा में ऐतिहासिक प्रक्रिया के विकास की सतत रूप से प्रभावित करने में समर्थ हैं, जिसकी आवश्यकता समस्त जनगण को है। शान्तिपूर्ण सहजीवन की नीति व्यवहार में इसी प्रकार अमल में लाई जा रही है।

जनविनाशकारी शस्त्रों की नई किस्मों और ऐसे शस्त्रों की नई प्रणालियों के विकास का परित्याग, नाभिकीय शस्त्रों की होड़ सीमित करने और समाप्त करने, सशस्त्र सेनाओं और परम्परागत हथियारों में कटौती करने जैसे कदमों के परिणाम अन्ततः नाभिकीय शस्त्रों का भण्डार घटाना तथा उनकी राजनीतिक और सैनिक रणनीतिक भूमिका को खत्म करना होता है। विश्व के कुछ भागों में और उसके बाह

विश्वव्यापी पैमाने पर सैनिक तनाव-जंघिल्य सुनिश्चित करने वाले कदम अधिक विस्तृत, स्थायी और संकेन्द्रित हो सकते हैं और बहुपक्षीय आधार पर एवं विभिन्न स्तरों पर अमल में लाए जा सकते हैं। यह अधिकाधिक दृढ़तर अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान होगा।”

परमाणु अस्त्रों के विरोध में शान्ति का यूरोपीय मोर्चा

परमाणु अस्त्रों के विरोध में यूरोपीय देशों की कई राजधानियों में अक्तूबर-नवम्बर 1981 में परमाणु अस्त्रों के विरोध में पश्चिमी देशों के समाचार-पत्रों में एक ओर जहाँ प्रसन्नता व्यक्त की गई वहाँ दूसरी ओर इन प्रदर्शनों को यूरोपीय शान्तिवादियों की विजय बनाया गया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाचार-पत्र ‘लमोँद’ ने अपने सम्पादकीय में इन प्रदर्शनों को अभूतपूर्व बताया। पत्र के विचारों में—

“अक्तूबर के अन्तिम दिनों में अनेक यूरोपीय देशों की राजधानियों में परमाणु अस्त्र-विरोधी प्रदर्शनों को इसलिए सफल कहा जाएगा कि इनमें भाग लेने वालों की संख्या लाखों में रही, स्वीडन को छोड़कर पेरिस, लन्दन, ब्रुसेल्स और रोम में प्रदर्शकारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। बेल्जियम में तो प्रदर्शनकारी आश्चर्यजनक रहा लेकिन इटली में तो कमाल ही हो गया। कम्युनिस्टों की पार्टियों के आह्वान पर कोई तीन लाख से अधिक लोग प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए एगत्र हो गए थे हालांकि इटली में कम्युनिस्ट पार्टियों का अधिक प्रभाव नहीं है। फ्रांस में परमाणु अस्त्र विरोध को देखते हुए प्रदर्शनकारियों की संख्या कम मानी जाएगी। फ्रांस की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने इन प्रदर्शनों का आयोजन किया था। आज वहाँ की समाजवादी सरकार भी अस्त्र सग्रह के विरुद्ध है लेकिन फ्रांस के प्रधान मंत्री यह भी कह चुके हैं कि किसी एक देश के एकतरफा निरस्त्रीकरण में कुछ नहीं हो सकता। फ्रांस के शान्ति आन्दोलन पर कम्युनिस्टों का बाकी प्रभाव है। परमाणु अस्त्र-विरोधी तारों में सोवियत समर्थन की कुछ भ्रष्टक मिल रही थी।

फिर भी परमाणु अस्त्रों का विरोध करने के लिए लाखों की संख्या में लोगों का पेरिस में उमड़ आना कोई साधारण बात नहीं है। कुल मिलाकर इन प्रदर्शनों में यही मिश्र होना है कि सन् 1950 के दशक में परमाणु बनाने पर रोक लगाने का जो अभियान चला था ठीक वंसी ही लहर आज यूरोपीय देशों में दिखाई पड़ रही है। नि.मन्देह सन् 1960 के दशक में शान्ति आन्दोलन एक नए रूप में सामने आया। जब से युद्ध न करने के लिए किसी एक या दूसरे पक्ष पर केवल दबाव डालने का आन्दोलन नहीं है। आज विश्व की दोनों शक्तियों की सहार-शमना सीमा पर पहुँच चुकी है। इसमें कौन बड़ी शक्ति बब बया कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या यह सारा मामला शान्तिपूर्ण बातचीत से तय किया जा सकता है? शान्तिवादियों का यूरोपीय देशों की सरकारों से यही अनुरोध रहा है कि वे समझदारी में काम लेकर बातचीत द्वारा भव्य मामला तय कर लें। पश्चिम यूरोपीय देशों में शान्ति आन्दोलनों में ही काम नहीं चलेगा। पूर्व-यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार के आन्दोलन की आवश्यकता है जहाँ उन क्षेत्र की एक महान् शक्ति के पास कम सहार शमना नहीं है।”

अमेरिकी दैनिक वाशिंगटन पोस्ट ने भी इन प्रदर्शनों पर टिप्पणी की। इस पत्र का विचार है कि लाखों लोगों के इन प्रदर्शनों में भाग लेने से स्पष्ट होता है कि बड़े देशों को अपनी सामरिक नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए—

“पश्चिमी यूरोप के चार बड़े देशों की राजधानियों में परमाणु शस्त्रों के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुए। इनमें पश्चिमी जर्मनी का प्रदर्शन सबसे बड़ा था। इन प्रदर्शनों से सोवियत संघ की अपेक्षा अमेरिका की कहीं अधिक संयत सीखना चाहिए। लन्दन, रोम, पेरिस और ब्रुसेल्स के प्रदर्शनों से पता चलता है कि परमाणु शस्त्रों के विरुद्ध आन्दोलन अब परम्परागत नहीं है, यह सामयिक राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। अमेरिका की अस्थिर-नैतिक इसकी ओर से उदासीन रही है। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों में परमाणु प्रस्न क्षेत्र में कोई बराबरी नहीं है। सामरिक महत्त्व के प्रस्न पर तो अमेरिका और सोवियत संघ की ही सामने-सामने बात होती है, लेकिन फिर भी आज यूरोपीय देश यह अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि परमाणु प्रस्न अमेरिका और सोवियत संघ के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी खतरनाक हैं। रीगन प्रशासन उस समय पश्चिमी यूरोप की कठिनाइयों को अनदेखी करके सोवियत संघ से मात्रात्मक भाषा में बात कर रहा है जिसका मतलब यह है कि प्रस्न-शस्त्रों के बारे में अमेरिकी नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। भले ही अमेरिका मनुलन बनाए रखने के लिए परमाणु शस्त्रों का निर्माण कर रहा हो, लेकिन परमाणु शस्त्र-विरोधी हाल ही के इन प्रदर्शनों के पीछे और भी गहरी बात है। प्रदर्शनकारियों का विचार है कि परमाणु शस्त्रों के निर्माण से सहयोगी यूरोपीय देश अपनी प्रमुखता खोते जा रहे हैं। ये प्रदर्शन किसी भी देश की रक्षा नीति पर बढ़ते हुए खर्च के विरुद्ध एक जबरदस्त चेतावनी है। इनसे यह भी सिद्ध होता है कि रक्षा पर इतने बड़े खर्च के लिए यूरोपीय जनता किसी भी दृष्टि से सहमत नहीं हो सकती।”

युद्ध की विभीषिका से आशंकित

यूरोपीय जनमत और सरकारों पर दबाव

यूरोपीय देशों की राजधानियों में परमाणु शस्त्र के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों में लोगों का बड़ी संख्या में शामिल होना यह साबित करता है कि अणु युद्ध के खतरे के प्रति यूरोपवासी सजग हो गए हैं। यूरोपीय देशों में इस प्रकार के प्रदर्शन अपना सानी नहीं रखते। लन्दन, रोम और ब्रुसेल्स में पाँच लाख से भी अधिक लोगों के जुलूस की एक ही माँग थी, “हमें बिप्पस की ओर न ले जाओ। पश्चिमी यूरोप में परमाणु शस्त्रों का प्रसार रोको।” इससे एक सप्ताह पहले ढाई लाखों लोगों का ऐसा ही एक जुलूस बोन में दिखाई पड़ा, जिसमें शामिल होने वालों ने भी यूरोप को परमाणु-शस्त्र का भण्डार बनाने के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रदर्शनों में शामिल होने वालों की इतनी बड़ी भीड़ 1960 के बाद पहली बार दिखाई दी, जब विएतनाम युद्ध के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। इस बार तो ऐसे लोग भी निःशस्त्रीकरण को बल देने के लिए घर से निकल पड़े थे जिन्होंने गत 30 वर्षों में किसी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए घर से बाहर कदम नहीं रखा था।

अचानक ही परमाणु अस्त्र विरोधी भावना के उफान के पीछे जो कारण हैं उनको कई नजरो से देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर वामपक्षीय तर्क काफी लोकप्रिय हुए हैं। विश्व शान्ति परिषद् को अपने प्रचार का माध्यम बना कर रूस इन भावनाओं को तूल देने में काफी सफल हुआ है, ऐसा दक्षिणपथियों का सोचना स्वाभाविक ही है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि आम जनता युद्ध से इतनी भयभीत है कि वह किसी भी कीमत पर लड़ाई का सामना नहीं करना चाहती। आनकित जनसाधारण को कुछ हद तक धर्म से भी बल मिला है, कि वह अपनी भावना को नीति निर्धारकों तक पहुँचा सके, चर्च के विचारों में जो परिवर्तन आया है उसमें परमाणु युद्ध को नहीं भी शह नहीं दी गई है।

चर्च की नई चिन्मनधारा से सबसे अधिक प्रभावित देश हालैंड है। वहाँ के अधिकांश गिरजों की प्रतिनिधि मस्या 'इन्टर चर्च पीस कौंसिल' के 20,000 सक्रिय सदस्य हैं, जो घर-घर जाकर निःशस्त्रीकरण का सन्देश फैलाते हैं। 1980 में एक धार्मिक सम्मेलन के दौरान हालैंड के धर्मगुरुओं ने वहाँ पर एकत्रित भीड़ को कहा था कि वे तहस-नहस करने के लिए परमाणु अस्त्र-शस्त्रों को साधन बनाए जाने का वहिष्कार करें। इन्हे कैथोलिक शान्ति आन्दोलन का भी पूरा समर्थन मिला, जिसका अनुदारवादी मत पर बहुत प्रभाव है।

वान, पश्चिम जर्मनी में विरोध प्रदर्शन का आयोजन दो प्रोटेस्टेंट चर्च की मस्याओं ने किया। ब्रूसेल्स के प्रदर्शन के बहुत से पादरियों, ईसाई संग्यासिनियों और ईसाई मजदूर मस्याओं के सदस्यों ने भाग लिया। कुल मिलाकर परमाणु विरोधी आन्दोलन में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक चर्च के मुकाबले अधिक सक्रिय रहा। जर्मनी के उत्तर में, प्रोटेस्टेंट-बहुल इलाका है, परमाणु विरोधी स्वर, दक्षिणी इलाकों की तुलना में अधिक मुखर था। फ्राँस और इटली जैसे देशों में, जहाँ कैथोलिक धर्मावलम्बी लोगों में अधिक हैं, परमाणु शस्त्रों का विरोध अधिक देखने की नहीं मिलता।

धर्म के अलावा और राजनीतिक विचार भी जनभावना को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। ब्रूसेल्स के प्रदर्शन में दो तिहाई मस्या ऐसे लोगों की थी जो फ्लेमिश (एच) भाषा बोलते हैं। बाकी एक तिहाई बेलून (फ्राँसीसी) भाषा बोलने वाले थे, हालाँकि दोनों भाषा बोलने वाले लोग कैथोलिक धर्मावलम्बी ही हैं। मजे की बात यह है कि फ्राँस और इटली में बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों ने परमाणु शस्त्रों के विरोधियों की संस्था कम कर दी है। साम्यवादी मार्क्सों में अपने सम्पर्क सूत्रों के बारे में बहुत सचेत हैं, इसलिए वे खुले तौर पर अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था की आलोचना करने से घबराते हैं।

हाल ही में कई देशों में परमाणु शस्त्रों के बारे में जो जनमत संग्रह हुए उनमें पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में जनसाधारण की मोच में कितना बड़ा भ्रमर आया है। नई जिन पाँच देशों में पशिम-2 प्रक्षेपणास्त्र स्थापित करना चाहता है, वहाँ के अधिकांश लोग तो प्रक्षेपणास्त्र के खिलाफ हैं या उनकी जरूरत के बारे में मन में सन्देह पालते हैं। यद्यपि कम ही लोग यह चाहते हैं कि उनका देश

नंटो से अलग हो जाए या तटस्थ रहे लेकिन साथ ही अधिकांश यही चाहते हैं कि सुरक्षा पर खर्च और न बढ़ाया जाए। नंटो के नीति निर्धारकों के लिए यह एक चिन्ताजनक बात है कि वे जिन देशों—ब्रिटेन, इटली, पश्चिम जर्मनी, हॉलैण्ड और बेल्जियम को प्रक्षेपणास्त्रों का गढ़ बनाना चाहता है उन्हीं देशों के लोग उनकी नीति को चुनौती दे रहे हैं।

ब्रिटेन के 50 प्रतिशत लोग प्रक्षेपणास्त्रों के खिलाफ हैं, जबकि 41 प्रतिशत उन्हें चाहते हैं। यही संस्थाएँ सितम्बर में क्रमशः 43 प्रतिशत और 49 प्रतिशत थीं। बेल्जियम में इसी महीने जो जनमत संग्रह हुआ उससे पता चला है कि 66 प्रतिशत लोग प्रक्षेपणास्त्र नहीं चाहते, केवल 19 प्रतिशत इन शस्त्रों का समर्थन करते हैं, जबकि केवल एक वर्ष पहले ये संस्थाएँ क्रमशः 42 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थीं। हॉलैण्ड में 68 प्रतिशत विरोधी और 28 प्रतिशत समर्थक हैं, जबकि गत वतभ्रम में ये संस्थाएँ क्रमशः 53 प्रतिशत और 39 प्रतिशत थीं। इटली में प्रक्षेपणास्त्रों के विरोधियों की संख्या कम नजर आती है, लेकिन वहाँ के जनमत संग्रह से प्राप्त विश्वसनीय तथ्य उललब्ध नहीं हैं। पश्चिम जर्मनी में जनमत संग्रह से प्राप्त तथ्य कुछ उलझे हुए हैं। मार्च में किए गए सर्वेक्षण में प्राप्त नतीजों में प्रक्षेपणास्त्रों के 39 प्रतिशत विरोधी और 39 प्रतिशत समर्थक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अब नंटो की बातचीत और प्रक्षेपणास्त्रों के संचार के निर्णय का प्रश्न आया तो 53 प्रतिशत लोग नंटो के समर्थक दिखाई पड़े। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जर्मनी की युवा पीढ़ी परमाणु शस्त्रों के घोर विरोधी हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला कि 20 वर्ष से कम उम्र वाले 70 प्रतिशत नए प्रक्षेपणास्त्रों के खिलाफ हैं।

ब्रितानी लोग, अन्य यूरोपीय देशों के लोगों की तुलना में, अमेरिका से अधिक हमदर्दी रखते हैं। युवा पीढ़ी के भी दो तिहाई सदस्यों का यही विचार है कि ब्रिटेन को तटस्थ न बनकर नंटो में रहना चाहिए, लेकिन एक पक्षीय परमाणु निःशस्त्रीकरण के समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। फ्रांस के पास अपने परमाणु शस्त्र हैं और वहाँ एकपक्षीय निःशस्त्रीकरण के समर्थकों की संख्या बहुत कम है। जनमत संग्रह से पता चलता है कि अधिकांश फ्रांसीसी लोग, स्वतन्त्र रूप से परमाणु जगत् में बने रहना है, फिर भी राष्ट्रपति मित्रों की रूस विरोधी नीति के बावजूद आम जनता तटस्थ रहने में आस्था रखती है। नंटो के सैनिक गठबन्धन में दोबारा फँसने के प्रति किसी का उत्साह नहीं है। 1980 के सर्वेक्षण से पता चलता है कि यदि रूस और अमेरिका में युद्ध छिड़ा तो फ्रांस के अधिकांश लोग उससे अलग ही रहना चाहेंगे। पेरिस में हुए प्रदर्शन में भाग लेने वालों की माँग थी कि परमाणु बमों पर रोक लगा दी जाए और सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले बम का रख मोड़ कर उसे नीमरी दुनिया की मदद के लिए खर्च किया जाए।

पश्चिम जर्मनी के लोग तो अब अपने देश की सुरक्षा के लिए भी लड़ने की तैयारी नहीं है और वे यह भी नहीं चाहते कि उनके लिए परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाए। मई में किए गए जनमत संग्रह से पता चलता है कि बहुत से लोग युद्ध

से बचने लिए अपने देश में साम्यवादी सरकार को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ।

हालैण्ड और बेल्जियम के लोगो का परमाणु शस्त्रों के प्रति घोर विरोध देखते हुए इन देशों की सरकारें अपने देशों में प्रक्षेपणास्त्रों की स्थापना के फैसले को स्थगित करने पर मजबूर हो गईं । नावो और डेनमार्क को परमाणु मुक्त इलाका बनाने की मांग भी बढ़ती जा रही है । इन दोनों देशों ने शान्ति के दौरान अपनी जमीन पर परमाणु शस्त्र लाने से इन्कार कर दिया है और अब यह सोचा जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में भी उनका इस्तेमाल न किया जाए ।

यह बनाना अभी सम्भव नहीं है कि यूरोप में परमाणु विरोधी आन्दोलन कितना फैलेगा, लेकिन इसकी गति निश्चिन ही बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं । पश्चिम जर्मनी में आने वाले अप्रैल में एक बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई गई है । जब वहाँ सोशल डेमोक्रेटो का सम्मेलन होगा । इस बीच परमाणु विरोधी शान्तिपूर्ण अवज्ञा की तैयारी में लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि वे शस्त्र बनाने वाले श्रमिकों को इन बात के लिए राजी कर पाएँगे कि वे परमाणु शस्त्र बनाने के औजारों को हाथ न लगाएँ ।



“यदि हम अपने आपको किसी एक गुट के साथ जोड़ लेते हैं तो एक प्रकार से शायद यह अच्छा कदम सिद्ध होगा। लेकिन हमें ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दुनिया को इससे नाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। इससे हम दुनिया में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकेंगे।” —जवाहरलाल नेहरू

गुट-निरपेक्षता अथवा असंलग्नता की नीति को सबसे पहले व्यावहारिक रूप देने का श्रेय भारत को है। इसे स्वतन्त्र भारत ने अपनी विदेश-नीति का आधार-स्तम्भ बनाया और भीषण बाधाओं के बावजूद इस नीति को आगे बढ़ाया। धीरे-धीरे गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने वाले देशों की संख्या बढ़ती गई। 1961 में बेलग्रेड के गुट-निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर-सम्मेलन में केवल 25 देश सम्मिलित हुए जबकि 1979 के हवाना शिखर सम्मेलन में सदस्य संख्या 94 हो गई। वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि जो भी राष्ट्र गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर स्वतन्त्र सम्प्रभु राष्ट्रों के रूप में उदित हो रहे हैं वे अधिकांशतः गुट-निरपेक्ष नीति को ही अपनाना अधिक अच्छा समझते हैं। कम्बोडिया वियतनाम तक ने गुट-निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया है। भारत विश्व के सभी गुट-निरपेक्ष देशों की ‘आशा’ है और विश्व-मंच पर भारत की आवाज का आज पहले से अधिक महत्व है। महाशक्तियाँ चाहे गुट-निरपेक्षता की नीति में हृदय से विश्वास न करती हो, लेकिन प्रचट रूप में इस नीति के प्रति वे सम्मान प्रदर्शित करती हैं। साम्यवादी चीन, जो विस्तारवादी और सैनिकवादी नीति का अनुसरण कर रहा है, स्वयं को गुट-निरपेक्ष कहलाना ही अधिक पसन्द करता है। पाकिस्तान जैसे देश के लिए गुट-निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कोई अर्थ नहीं रखता, फिर भी मजे की बात यह है कि गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में प्रवेश का प्रयत्न करता रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुट-निरपेक्षता की नीति आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में स्थायी रूप धारण कर चुकी है और एक ‘वास्तविकता’ बन गई है।

गुट-निरपेक्षता का अर्थ और उसके तत्त्व

गुट-निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति-मुट्टों से तटस्थ या अलग रहते हुए अपनी स्वतन्त्र निर्णय-नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्पण

देना। इसका अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 'तटस्थता' (Neutrality) नहीं है। गुट-निरपेक्ष देश विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति अपनाते हैं जो विश्व-शान्ति कायम रखने में सहायक हो। भारत सरकार के एक प्रकाशन के अनुसार—“गुट-निरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतन्त्र रीति-नीति। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य-अनौचित्य को देखा जा सकता है। एक गुट के साथ मिलकर उचित-अनुचित का विचार किए बिना आँख मूँदकर पीछे-पीछे चलना गुट-निरपेक्षता नहीं है।” ‘तटस्थता’ और ‘गुट-निरपेक्षता’ पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। इनमें यह समानता तो है कि दोनों के अन्तर्गत शीतयुद्ध के समय सघर्ष से अलग रहा जाता है, लेकिन आधारभूत अन्तर यह है कि जहाँ वास्तविक युद्ध छिड़ने पर एक तटस्थ राष्ट्र युद्ध से अलग रहता है, वहाँ गुट-निरपेक्ष देश युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से उलझ सकता है। न्याय का समर्थन करते हुए उमकी विदेश-नीति सकारात्मक रूप में संचालित होती है। स्विट्जरलैंड एक ‘तटस्थ’ देश है जबकि भारत एक ‘गुट-निरपेक्ष’ देश है। गुट-निरपेक्षता के अप्रदूत प. नेहरू ने कहा था—“मैं ‘तटस्थ’ शब्द का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्धकाल में होता है। शान्ति-काल में भी इससे एक प्रकार के युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है।” जॉर्ज लिस्का ने लिखा है कि—“किसी विवाद के सन्दर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किन्तु असलग्नता या गुट-निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद कर सदैव सही नीति का समर्थन करना।”

गुट-निरपेक्षता कोई निष्पक्ष सिद्धान्त नहीं है। यह एक सक्रिय और स्वतन्त्र सिद्धान्त है। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से गन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। गुट-निरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है किमी भी देश के साथ सैनिक गुटबन्दी में सम्मिलित न होना, पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बँधना, हर प्रकार की आक्रामक सन्धि से दूर रहना, ग्रीनयुद्ध से पृथक् रहना, राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश-नीति का संचालन करना। सन् 1961 में गुट-निरपेक्षता के तीन कर्णधारों—नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके पाँच आधार अथवा तत्त्व स्वीकार किए थे—

- (1) सदस्य-देश स्वतन्त्र नीति पर चलता हो;
- (2) सदस्य-देश उपनिवेशवाद का विरोध करना हो;
- (3) सदस्य-देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो;
- (4) सदस्य-देश ने किमी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो; एवं

(5) सदस्य-देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक बढ़ा बनाने की इजाजत न दी हो।

गुट-निरपेक्षता की जो बुनियाद भारत ने सन् 1946-47 में रखी वह गम्य के साथ और भी अधिक मजबूत बन चुकी है। प. नेहरू के ये शब्द आज भी इस नीति के सन्दर्भ में सजीव हैं—

“जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होना हो वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे।”

पाकिस्तान ने अत्याचारों से छुटकारा दिलाकर बंगलादेश के उदय में भारत ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह प. नेहरू के उपर्युक्त शब्दों की पुष्टि कर देती है। इससे सिद्ध हो जाना है कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ ‘योया शान्तिवाद’ नहीं है। यह निर्मयता और साहस की नीति है, कायरता की नहीं। गुट-निरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक है—यह अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखती बल्कि दोनों पक्षों की स्थिति को समझकर उचित पक्ष के समर्थन को तत्पर रहती है। गुट-निरपेक्ष नीति में धास्या रखने वाले देश सैनिक मन्थियों का विरोध करते हैं और मानते हैं कि इस प्रकार की सन्धियाँ सहयोग का नहीं बरन् विरोध का परिणाम होती हैं जिन्हें तोड़ने का एकमात्र उपाय युद्ध अथवा पारस्परिक घोर वैमनस्य है।

गुट-निरपेक्षता और तटस्थता (Non-alignment and Neutrality)

प्रायः गुट-निरपेक्षता की तटस्थता से विभूषित किया जाता है जबकि दोनों एक नहीं हैं। तटस्थता में जहाँ नकारात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है और यह केवल एक वास्तविक युद्ध की अवधि तक सीमित है, वहाँ गुट-निरपेक्षता का विचार सक्रिय, सकारात्मक और निश्चिन्त है। दोनों सिद्धान्तों में कोई जन्मजात समानता नहीं है—जब इनका प्रयोग शीतयुद्ध के सम्बन्ध में हो। तटस्थता का परिवर्तनशील मिद्धान्त गुट-निरपेक्षता के विचार को शीतयुद्ध या परमाणुशान्ति की अवधि में ही अपने अन्तर्गत समाहित किए हुए है। प. नेहरू ने स्वयं यह स्वीकार किया था—
“अगर आप आज के युग को शीतयुद्ध से व्याप्त मानते हैं तो हम निश्चिन्त रूप से तटस्थ हैं।”¹

संयुक्त अरब एगाराय में, गुट-निरपेक्षता एक सकारात्मक तटस्थता है। पश्चिमी कूटनीतिक क्षेत्रों में तटस्थता के जो सामान्य अर्थ हैं उसे प्रकीर्ण व एशिया के निवासी अधिकांश नकारात्मक मानते हैं। स्वर्गीय नारिर ने कहा था— “मैं सोचना हूँ कि तटस्थता का प्रयोग गलत है। एक अच्छा शब्द गुट-निरपेक्षता है। तटस्थता शब्द का निर्माण केवल युद्ध के समय के लिए हुआ है। हम नैतिक रूप से

तटस्थ नहीं हैं लेकिन हम गुट-निरपेक्ष हैं इसलिए हम प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का न्याय उसके गुणों के आधार पर करते हैं, न कि गुटवाद के आधार पर। यदि अमेरिका गुट-निरपेक्ष होता तो आप भी अलजीरियन समस्या पर एक साहसी मत प्रकट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आप फ्रांस के मित्र हैं आप अलजीरिया के राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं कर सकते।”

तटस्थता और गुट-निरपेक्षता के मध्य एक निकट और समानान्तर तुलना करने पर निम्नलिखित अन्तर सम्मुख आते हैं—

1 तटस्थता दो आग्रामकों और उनके मध्य के सघर्ष के प्रति उदासीनता के दृष्टिकोण का दावा करती है। गुट-निरपेक्षता ऐसा कुछ नहीं करती। इसके विपरीत, यह प्रत्येक समस्या की उसके गुण के आधार पर न्याय करती है और अपने स्वतन्त्र मत की घोषणा करती है। यह एक कल्याणकारी और समाजवादी प्रकृति के राज्य में सामाजिक न्याय का स्वागत करती है और उसी समय व्यक्तिगत पूंजीवाद माहूस के माध्यम से औद्योगीकरण को भी प्रोत्साहन देती है।

2 तटस्थता का तात्पर्य एकाकीपन की अवस्था है जबकि गुट-निरपेक्षता अफ्रीका-एशिया की जनता को अपना भविष्य निर्माण करने में सहायता देती है। न तो यह स्विट्जरलैंड और स्वीडन की स्थायी तटस्थता है और न अमेरिका का विध्यात्मक एकाकीपन ही।

3 गुट-निरपेक्षता तटस्थता नहीं है क्योंकि वह अपने दृष्टिकोण और विचारों में विध्यात्मक है। गुट-निरपेक्षता का आशय अन्तर्ग्रस्त होने से मुक्तता नहीं है वरन् यह अन्तर्ग्रस्तता की अपरिहार्यता से उत्पन्न होनी है।

4 स्विस् सरकार के विपरीत गुट-निरपेक्ष राष्ट्र बिना गुट का निर्माण किए हुए विश्व समस्याओं पर सहयोग करते हैं (उदाहरण के लिए कांगो, स्वेज, न्यूजा मकट आदि)।

स्पष्ट है कि गुट-निरपेक्षता की नीति का उद्देश्य युद्ध के सम्बन्ध में एक तटस्थ स्थिति को खोज करना नहीं है। इसका अर्थ स्वतन्त्रता, स्थायी शान्ति और सामाजिक न्याय के लिए निरन्तर सक्रिय कार्य करना है। प्रो. पीटर के अनुसार, जीतयुद्ध में मयुक्त राज्य और मोवियत सघ द्वारा प्रेरित शक्तियों के मध्य चल रही राजनीतिक या ब्रूटनीतिक प्रतिद्वन्द्विता में किसी भी पक्ष का समर्थन करने से इनकार करना ही तटस्थता है। दूसरी ओर गुट-निरपेक्षता का अभिप्राय है बिना किसी के साथ पूरी तरह बंधे हुए अपनी स्वतन्त्र नीति का पालन किया जाए।¹

गुट-निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक (Factors Promoting Non-alignment)

गुट-निरपेक्षता के विषय में अनेक तत्त्वों ने योग दिया है। इसके विराम में मन्दमें में सर्वप्रथम हमें यह देयना जाहिए कि कोई देश अपनी स्वतन्त्रता को दाय

पर लगाकर भी सैनिक सन्धियों में सम्मिलित क्यों होना चाहता है और गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए कौनसी प्रेरणाएँ काम करती हैं।

सैनिक सन्धियों में आबद्ध होने के कारण

आखिर सैनिक सन्धियों के प्रति आकर्षण क्यों है ? यथार्थ में कोई भी राष्ट्र अपनी स्वेच्छा से उन सम्बन्धों को स्वीकार नहीं करना चाहता जो सैनिक सन्धियों से आबद्ध होने पर उन पर लग जाते हैं। प्रत्येक सन्धिवद्ध देश प्रायः यही सोचता है कि वर्तमान परिस्थितियों में सन्धिवद्ध होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। कई बार बड़ी शक्तियाँ सैनिक शक्ति के प्रयोग की धमकी देकर कमजोर राष्ट्रों को सन्धिवद्ध होने के लिए मजबूर करती हैं। जर्मनी, कोरिया, वियतनाम की स्थिति से विदित होता है कि इन देशों के जब एक भाग का समर्थन पश्चिमी शक्तियों ने आरम्भ किया तो स्वभावतः दूसरा भाग साम्यवाद की ओर झुका। इन देशों के दोनों भागों ने परिस्थितियों के दबाव में आकर महाशक्तियों के साथ सैनिक सन्धि में बंध जाना उचित समझा। ध्यान रहे कि बाध्यकारी रूप से किसी भी देश को सदैव सन्धिवद्ध नहीं रखा जा सकता। यदि किसी देश के साथ सन्धि को दीर्घायु बनाना है तो आवश्यक है कि उस देश में ऐसी संस्थाओं और सरकार की स्थापना हो जो सन्धि-युक्त नीति का समर्थन करे। द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप का और पश्चिमी शक्तियों के यूनान, इटली एवं मध्यपूर्व तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में हस्तक्षेप का कारण इन प्रदेशों में ऐसी सरकारें कायम करना था जो नव्यन्धिन महाशक्ति के साथ सन्धिवद्ध रह सकें। कोई भी देश बड़ी शक्तियों के साथ जिन कारणों से सन्धिवद्ध होता है, उनमें कुछ प्रमुख ये हैं—

1. जिस देश से आक्रमण की आशंका होती है उसके विरुद्ध दूसरी शक्ति के साथ सन्धिवद्ध हो जाना उचित समझा जाता है। आक्रमण की समस्याएँ तब अधिक स्पष्ट हो जाती हैं जब दो राष्ट्र परस्पर राजनीतिक संघर्ष में उलझ जाते हैं। उदाहरणार्थ, मई 1950 में थाईलैण्ड, दक्षिण-वियतनाम आदि राज्यों को विश्वास था कि यदि घेराबन्दी न की गई तो चीन के आक्रमण लगातार होते रहेंगे; दूसरी ओर चीन यह सोच रहा था कि यदि किसी उपनिवेशवादी सरकार को थोड़ा बहुत भी स्थानीय समर्थन मिला तो विदेशी सहायता प्राप्त कर वह चीन के लिए एक चुनौती बन जाएगी।

2. शीतयुद्ध के फलस्वरूप भी देश प्रायः महाशक्ति के साथ सैनिक रूप में सन्धिवद्ध हो जाते हैं ताकि संकट के समय उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड आदि देश साम्यवाद के विरुद्ध अमेरिका के साथ सन्धिवद्ध हैं, यद्यपि इनमें से कोई आन्तरिक रूप से साम्यवादी समस्या से ग्रस्त नहीं हैं और न ही उनके सामने कोई अन्तर्देशीय अथवा विदेशी साम्यवाद की चुनौती है। शीतयुद्ध की सन्धियों का एक ज्वलन्त उदाहरण पाकिस्तान है। विचित्र विडम्बना है कि पाकिस्तान में ये स्थितियाँ पाई जाती हैं जो गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने के लिए सहायक हैं, फिर भी पाकिस्तान सैनिक गुटबन्दी का मार्ग अपनाए हुए है।

3. आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता भी किसी देश को सैनिक-सन्धियों में आवद्ध होने के लिए विवश करती है। उदाहरणार्थ, युद्ध के तुरन्त बाद फिलिपाइन और मलाया की आन्तरिक अवस्था ने इन देशों को सैनिक सन्धि में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है।

4. सैनिक सन्धि में आवद्ध होने का एक कारण तब उत्पन्न होता है जब शीतयुद्ध का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, विदेशी एजेन्टों द्वारा किसी देश की आन्तरिक अव्यवस्था को प्रेरित या समर्थित किया जाता है। यार्डलैंड तथा उससे सलग्न क्षेत्र, अफ्रीका के अनेक राज्यों, मध्य-पूर्व और लेटिन अमेरिका के बहुत से राज्यों पर यही कारण लागू होता है।

गुट-निरपेक्षता की प्रेरक शक्तियाँ

कोई देश गुट-निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाता है, इसके अनेक कारण हैं। ऐसा नहीं होना कि जिस देश पर सन्धिबद्ध होने के लिए दबाव न डाले जाएँ वह स्वतः ही गुट-निरपेक्षता की नीति अपना लेता है। सन्धिबद्धता के कारणों का प्रभाव निषेधात्मक रूप से महत्त्वपूर्ण हो सकता है। किन्तु सकारात्मक रूप से इस दिशा में प्रेरित करने वाले दूसरे ही तत्त्व होते हैं। विलियम हैंडर्सन (William Handerson) ने गुट-निरपेक्ष नीति के लिए उत्तरदायी आठ मुख्य प्रेरणाओं का उल्लेख किया है। ये हैं—पश्चिमीकरण का विरोध, नव प्राप्त स्वतन्त्रता को कायम रखने का संकल्प, भावनाओं की प्रगाढ़ता किन्तु भौतिक बमजोरियाँ, विदेश-व्यवहार की अज्ञानता अथवा उदासीनता, मार्क्सवाद का प्रभाव, साम्यवादी चीन के साथ समायोजित होने की आवश्यकता, यह विश्वास कि गुट-निरपेक्ष नीति शान्ति को बढ़ावा देती है तथा गुट-निरपेक्षता द्वारा साम्यवाद को रोका जा सकता है।

गुट-निरपेक्षता की सहायक परिस्थितियों अथवा प्रेरणाओं में निम्नलिखित मुख्य हैं—

1. प्रथम प्रेरक शक्ति राष्ट्रवाद की भावना है। राष्ट्रवाद और गुट-निरपेक्षता के बीच सहयोग इसी बात से स्पष्ट है कि नवोदित राष्ट्रों के नेता अपनी गुट-निरपेक्षता के समर्थन में राष्ट्रवाद का सहारा लेते रहे हैं। जॉन मारक्स का कहना है कि फ्राँस, जर्मनी तथा ग्रेट ब्रिटेन में जब कभी तटस्थता की नीति का प्रभाव हुआ है तो वह मुख्यतः इन देशों में व्याप्त राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही है।

2. दूसरी सहायक परिस्थिति उपनिवेशवाद का विरोध है। बाँटुंग सम्मेलन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि यदि किसी देश की सैनिक-संगठन में शामिल होने को मजबूर करने वाली कोई स्थिति नहीं है तो उपनिवेश-विरोधी भावना उसे गुट-निरपेक्षता की दिशा में प्रेरित करेगी। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राज्य यह अनुभव करते हैं कि यदि वे बड़े राष्ट्रों के साथ सैनिक सन्धियों में आवद्ध हों गएँ तो शोषक और शोषित राज्यों के सम्बन्धों का वही पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। इन देशों के साथ एक बड़ी असामञ्जस्यपूर्ण स्थिति है। उपनिवेश-विरोधी भावना के कारण एक ओर तो वह पश्चिमी शक्तियों के साथ

संयुक्त होना नहीं चाहते, दूसरी ओर अतीत के प्रशासनिक और अन्य सम्बन्धों के कारण वे उसका विरोध भी नहीं करना चाहते। इसलिए वे गुट-निरपेक्षता की नीति का ही महारा लेते हैं। गुट-निरपेक्षता की नीति वास्तव में उनके लिए असामञ्जस्य के समाधान और अन्तम-रक्षा का एक प्रभावपूर्ण साधन बन गई है।

3. तीसरी सहायक परिस्थिति नवोदित राज्यों की अर्द्ध-विकसित स्थिति है। इन देशों की रूचि शास्त्रास्त्रों की प्रतियोगिता में बचकर आर्थिक पुनर्निर्माण में अधिक है और केवल गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाकर ही ये देश विश्व के विरोधी गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाते हैं। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का तर्क है कि उन्हें जो भी विरोधी सहायता मिल रही है वह उनका अधिकार है, न कि उन पर कोई अहसान। स्वर्गीय राष्ट्रपति नासिर का तर्क था कि अतीत में साम्राज्यवादी शक्तियों ने जिस राष्ट्रीय सम्पत्ति का अपहरण किया वह यदि उन्हें वापस मिलनी है तो इसमें किसी का भी क्या अहसान है। सहायता देना उन्नत राष्ट्रों का कर्तव्य है। यह एक प्रकार का कर है जो अतीत के उपनिवेशवादी शोषकों द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाना चाहिए जो शोषित हुए हैं।

4. गुट-निरपेक्षता की नीति का एक जातीय और सांस्कृतिक पहलू भी है। इस नीति के समर्थक देश मुख्यतः अफ्रीका और एशिया हैं जिनका यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा आर्थिक रूप से शोषण किया गया था और जिन पर इनका राजनीतिक प्रभुत्व रहा। ये गुट-निरपेक्ष देश अश्वेत हैं, जातीय और सांस्कृतिक दृष्टि से उनमें बहुत कुछ समानता है। यद्यपि सांस्कृतिक एकता की कड़ियाँ मजबूत नहीं हैं, तथापि इस रूप में एकता है कि अब वे समान रूप से किसी भी बड़ी शक्ति के अधीन नहीं रहना चाहते।

श्री विलोकीनाथ कौल ने गुट-निरपेक्षता के हल के पीछे अथवा 'विरोधी-गुटों द्वारा अयथार्थवादी शक्ति-सन्तुलन कायम करने के प्रयत्नों के निवारण' के पीछे जो विचार निहित है उसके चार पहलू स्पष्ट किए हैं। श्री कौल के अनुसार—

पहली बात तो यह मान्यता है कि स्थायी सन्तुलन-शक्ति की राजनीति के अभाव में ही कायम किया जा सकता है।

दूसरे, यह विश्वास है कि खतरनाक किरम का शक्ति-सन्तुलन कायम करने की होड़ का प्रादुर्भाव तन्हेह, आणका और अविश्वास के कारण होता है। इस प्रकार के वातावरण की शुद्धि के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उदीयमान देश ही इस तरह की भूमिका भदा कर सकते हैं क्योंकि उनका बोझ कम है और वे पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं।

तीसरे, गुटों के बीच आपसी प्रतिद्वन्द्विता नए राष्ट्र की परिस्थितियों के लिए अशासनिक और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हानिकारक है। इतना ही नहीं, उनका अन्तिमपूर्वक विचार करने की महती आवश्यकता के मार्ग में भी यह एक बाधा है।

चौथे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति-सन्तुलन की धारणा अग्रगतिशील है और इसका आधार पक्षपात तथा अन्याय को कायम रखते हुए यथास्थिति बनाए रखना है। दूसरी तरफ नए राष्ट्रों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे एक ऐसे भविष्य की कामना करें जो पक्षपातपूर्ण अतीत के गहित भार से मुक्त है।

निर्गुट आन्दोलन का विकास

निर्गुट देशों का पहला औपचारिक सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था, हालाँकि इसकी दुनियाद पाँच वर्ष पहले 1956 में नेहरू-नासिर और टीटो द्वारा ब्रियोनी में रखी जा चुकी थी। तीसरी दुनिया के इन तीन दिग्गजों के आंतरिक विचार-विमर्श के बाद 1956 में एक मसविदे पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें निर्गुट आन्दोलन के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए थे।

यों एक लम्बे अर्से से ये तथा अन्य स्वतन्त्रचेता देशों के नेता महती शक्तियों का दबाव भेँलते हुए बीच का रास्ता निकालने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे, लेकिन छठे दशक में कोरियाई युद्ध ने इस सलक को तेज कर दिया। 1956 में भारत, मिस्र और युगोस्लाविया, तीनों सुरक्षा परिषद् के सदस्य थे और उन पर दोनों महती शक्तियों द्वारा इधर या उधर झुकने के लिए निरन्तर दबाव पड़ रहा था। कई विकासशील देश सैनिक गठबंधनों के जरिये या दबाव के कारण किसी न किसी खेमे में पिछलग्गू बन गये थे। अकेला न पड़ते हुए नही रास्ते पर चल पाने के लिए जरूरी था कि अगुआ निर्गुट देशों में आपसी तालमेल हो और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के बारे में यथासंभव समान नीतियाँ बनाई जा सकें। इस ऐतिहासिक आवश्यकता को व्यावहारिक रूप देने की पेशकश इस आंदोलन के जन्म का कारण बनी।

1956 और 1961 निर्गुट आन्दोलन के दो महत्वपूर्ण आरम्भिक चरण थे, लेकिन तीसरी दुनिया के देशों में अपना रास्ता खुद चुनने की आकांक्षा इसके पहले से मौजूद थी। कम से कम भारतवर्ष इस चेतना को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने और एशियाई अफ्रीकी देशों को एक मंच पर लाने के लिए पाँचवें दशक से ही उत्सुक था। औपचारिक रूप से स्वाधीन होने के 11 महीने पहले ही अंतरिम सरकार के अध्यक्ष की हैसियत से जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितम्बर, 1946 को एक रेडियो प्रसारण में कहा था—हम चाहते हैं कि एक-दूसरे के खिलाफ गुटबाजी से हम यथामंभव अलग रहें। इस (सिमेबंदी) के कारण ही अतीत में विश्वयुद्ध हुए हैं और भविष्य में अधिक बड़े पैमाने पर विपत्ति आ सकती है। उसी वर्ष 13 दिसम्बर को नेहरू ने कहा था “हम सभी देशों से मित्रो चाहते हैं। निर्गुट होने का मतलब अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की उपेक्षा नहीं है—इसका मतलब है स्वतन्त्र विदेश नीति।”

आधिकारिक रूप से पिछड़े हुए कमजोर देश, जो बल तक किसी साम्राज्य के उपनिवेश थे पूर्ण स्वतन्त्र विदेश नीति पर नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन यदि इन तरह के लगभग देशों को एक मंच पर हो जाने पर महती शक्तियों ने मुकाबले उनके समवेत स्वर का बजन बढ़ जाना है।

भारत की पहल पर नई दिल्ली में 1947 के आरम्भ में एशियाई संघ सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अनेक देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। एशियाई देशों की चिंता इस प्रकार व्यक्त हुई थी—“हम एशिया के देश एक असें तक पश्चिमी दरबारों और दूतावासों में परियाद करते रहे हैं। अब यह प्रतीत की चीज हो जानी चाहिए। हम उन सभी से सहयोग करना चाहते हैं जो हम से सहयोग करना चाहें। हम दूसरों के हाथ में नहीं खेलना चाहते हैं।”

अप्रैल, 1955 में आयोजित वाइंग सम्मेलन (इंडोनेशिया) ऐसे ही व्यापकतर प्रयास की एक और कड़ी था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में, यद्यपि भारत और चीन की आपसी झगडाट उभर कर सामने आयी तथापि उसका मुख्य स्वर यही रहा कि महुती शक्तियाँ अपने फंसले दूसरों पर न लाईं इस सम्मेलन में अनुमोदित मिढान्त निर्गुट आन्दोलन के हिस्से बने। इस दृष्टि से भारत चीन का बाणिज्य व्यापार समझौता (1954) भी उल्लेखनीय है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में जिन पाँच सिद्धान्तों का उल्लेख है, और जो पञ्चशील के नाम से प्रसिद्ध हुए, आगे चलकर निर्गुट आन्दोलन के व्यावहारिक सिद्धान्त के रूप में अपनाये गये। ये सिद्धान्त थे— (1) एक दूसरे की क्षेत्रीय अलडता और प्रमुसत्ता का सम्मान, (2) एक दूसरे पर हमला न करना, (3) एक दूसरे के अदखली मामलों में दखल न देना, (4) समानता और परस्पर लाभ, (5) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व।

कोरियाई युद्ध और समुक्तराष्ट्र संघ में बड़ी ताकतों की नीतियों के कारण न केवल निर्गुट आन्दोलन का मच्च विकसित होने में मदद मिली बरन् समुक्तराष्ट्र में एशियाई और अरब देशों को भी नजदीक ला दिया। धीरे-धीरे इस वर्ग में अफ्रीकी देश भी शामिल होने लगे। धीरे-धीरे अब समुक्तराष्ट्र में अफ्रीकी एशियाई देशों का बहुमत हो गया है और निर्गुट देशों की संख्या 92 हो गई है। यह संख्या समुक्तराष्ट्र सदस्यों की कुल संख्या की दो तिहाई है।

73 सदस्य देशों के विदेशमन्त्रियों के अलावा 17 और देशों के 9 अन्तर्राष्ट्रीय मंडलों के प्रतिनिधियों ने प्रेक्षक की हैसियत से नई दिल्ली सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके अलावा 7 देश और 18 संगठनों के प्रतिनिधि अतिथि की हैसियत से आये। देखिए ‘राष्ट्र’।

1961 से लेकर अब तक निर्गुट देशों के पाँच शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। मंत्री और अधिकारी स्तर के सम्मेलनों की संख्या इसके अलावा है।

पहला निर्गुट शिखर सम्मेलन 2 सितम्बर, 1961 को वेलपेट में हुआ था, जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन होने तक निर्गुटता का सिद्धान्त पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था—कम से कम भारत की तटस्थता को अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी द्वारा, अतमने ढग से ही सही, मान्यता मिल चुकी थी।

पहले सम्मेलन से निर्गुट देशों को एक स्वतन्त्र मच्च लो मिल गया, मगर इन देशों की शासन प्रणालियों, राजनैतिक विश्वासों, आर्थिक स्थिति के स्तरों, भौगोलिक तत्वाओं और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में इतना अन्तर था कि उनमें

भीतरी एकता का खासा अभाव था कि जो सैनिक संगठनों की मार्फत किसी खेमे में शामिल नहीं हुए थे उनमें से भी अनेक आर्थिक अथवा अन्य कारणों से बड़ी ताकतों से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे।

दूसरा शिखर सम्मेलन वाहिरा (अक्टूबर 1964) में हुआ तब तक प्रधनमंत्री नेहरू का देहान्त हो चुका था और 1962 में चीनी हमले के प्रति निर्गुट देशों की उदासीनता भारत के लिए पीड़ाजनक अनुभव बन चुकी थी। बहराल इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने निर्गुट देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहा, मगर वह मिला नहीं। यह स्थिति खुद निर्गुट आन्दोलन के लिए प्रीतिकर नहीं रही। 1964 से 1970 तक भारत ने निर्गुट आन्दोलन में सक्रिय हिस्सा नहीं लिया और यह आन्दोलन भी द्विविधा की स्थिति में रहा। लेकिन इस बीच अफ्रीका, लेटिन अमेरिका और कैरेबियन सागर के देशों की दिलचस्पी इस मंच में में बढ़ी और सितम्बर, 1970 में तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका (अफ्रीका) में हुआ। इसमें 60 देशों ने हिस्सा लिया।

लुसाका सम्मेलन निर्गुट देशों की नई आर्थिक मोर्चेबन्दी के लिए हमेशा याद किया जायेगा। पहली बार विकासशील देशों में आपसी आर्थिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। संभवतः इसका कारण यह था कि इस बीच समुत्तराष्ट्र के तत्वावधान में व्यापक और विकास सम्मेलन (अकटाड) का गठन हो चुका था और तीसरी दुनिया के देश अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो चुके थे।

चौथा निर्गुट सम्मेलन अल्जियर्स (1973) में और पाँचवाँ 1976 में कोलम्बो में हुआ। अल्जियर्स सम्मेलन में 47 सदस्य देश जमा हुए और अनेक यूरोपीय देश प्रेक्षक की हैसियत से आये। इस सम्मेलन में ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पहलुओं पर जिनका संबंध विकासशील देशों से है, विशेष रूप से विचार किया गया।

पाँचवें कोलम्बो सम्मेलन (1976) में निर्गुट आन्दोलन की उपलब्धि और सीमाओं का विस्तार से विवेचन हुआ। 73 सदस्यों ने इस शिखर सम्मेलन में समन्वय कार्यालय (कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो) की स्थापना का निश्चय किया गया। सदस्यों की संख्या 25 रखी गई—अफ्रीका 12, एशिया 8, लेटिन अमेरिका 4 और यूरोप 1। इस कार्यालय के सदस्य देशों की पहली बैठक 1977 में नई दिल्ली में हुई थी। नितम्बर, 1979 में गुट-निरपेक्ष देशों के छठे शिखर सम्मेलन (हवाना) में सदस्य संख्या 94 हो गई।

निर्गुट आन्दोलन के अधिकतर देश गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं भूतपूर्व उपनिवेश हैं और आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। ऐतिहासिक कारणों से उनके आपसी भगड़े और विवाद भी कम नहीं हैं। महत्वाकांक्षाएँ, महुती शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता और अन्य विमर्शिताएँ कई बार उन्हें आपस में लड़ा देती हैं और बदवर्ती परिस्थितियों के अनुसार नये-नये समीकरण बनाने की मजबूरी पंदा करती हैं।

अब दुनिया सीधे दो खेमों में नहीं बँटी है—चीन, भारत, जापान आदि मभीनी ताकतों के उभरने से निर्गुट आन्दोलन के भीतर नये भगड़े और नये

समीकरण बने हैं, फिर भी इन देशों को निर्गुट मंच की आवश्यकता है और आगे भी बनी रहेगी। इस बीच अनेक क्षेत्रीय संगठन (इस्लामी सम्मेलन, एशियान, तेन निर्णायक संगठन आदि) बन गये हैं, फिर भी निर्गुट आन्दोलन की उपयोगिता कम नहीं हुई है, निर्गुट आन्दोलन ने अपनी सारी कमजोरियों और विफलताओं के बावजूद विकासशील देशों को आत्मसम्मान और गौरव दिया है और एक ऐसा अनोखा मंच भी जहाँ से वे अपनी विरादरी के देशों की आशाओं और आकांक्षाओं को बाणी दे सकते हैं।¹

गुट-निरपेक्ष देश

वर्तमान में जो गुट-निरपेक्ष देश, निर्गुट आन्दोलन में सम्मिलित हैं, वे ये हैं—

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. अफगानिस्तान | 27. मलयेशिया |
| 2. अल्जीरिया | 28. मालदीव |
| 3. अंगोला | 29. माली |
| 4. बहरैन | 30. माल्टा |
| 5. बाह्रतीना | 31. मारितानिया |
| 6. बंगलादेश | 32. मारिशस |
| 7. बेनिन | 33. मोरक्को |
| 8. भूटान | 34. मोजम्बिक |
| 9. बोलीविया | 35. नेपाल |
| 10. बोत्स्वाना | 36. निकारागुआ |
| 11. बुरुंडी | 37. नाइजर |
| 12. कैमरून | 38. नाइजीरिया |
| 13. केप वर्दे | 39. ओमान |
| 14. म० अफ्रीकीय | 40. पाकिस्तान |
| 15. चैड | 41. पी. एल. मो. |
| 16. कोमोरो | 42. पनामा |
| 17. कांगो | 43. पेरू |
| 18. क्यूबा | 44. कतार |
| 19. सिप्रस | 45. साडा |
| 20. जिबूती | 46. सामो त्रोमो त्रि |
| 21. मिस्र | 47. सऊदी अरब |
| 22. इक्वे. गिनी | 48. सेंट लूसिया |
| 23. इथियोपिया | 49. सेनेगल |
| 24. गबोन | 50. सेशेलस |
| 25. गांबिया | 51. सिचरे निग्रो |
| 26. घाना | 52. रैडगापुर |

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 53. ग्रेनाडा | 74. सोमालिया |
| 54. गिनी | 75. एस. डब्ल्यू ए. पी. ओ. |
| 55. गिनी बिसाऊ | 76. श्रीलंका |
| 56. गुयाना | 77. सूडान |
| 57. भारत | 78. सूरीनाम |
| 58. इंडोनेशिया | 79. रवांडीलैंड |
| 59. ईरान | 80. सीरिया |
| 60. इराक | 81. ताजानिया |
| 61. साइबरी कोस्ट | 82. टोगो |
| 62. जमैका | 83. त्रिनिडाड तो. |
| 63. मुर्दानि | 84. तुनीसिया |
| 64. केन्या | 85. उगांडा |
| 65. उ. कोरिया | 86. स. अरब |
| 66. कुवैत | 87. अफर बोल्टा |
| 67. लाओस | 88. वियतनाम |
| 68. लेबनान | 89. उत्तर यमन |
| 69. लेसोथो | 90. द. यमन |
| 70. लाइबेरिया | 91. युगोस्लाविया |
| 71. लीबिया | 92. जेमरे |
| 72. मेडागास्कर | 93. जाबिया |
| 73. मलावी | 94. जिबाव्वे |

गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन 9 से 13 फरवरी 1981 तक नयी दिल्ली में हुआ, जिसके फलस्वरूप गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की एकरा और एकजुटता काफी मजबूत हुई तथा आपसी मतभेदों के बावजूद गुट-निरपेक्ष देशों की विभिन्न मंगलों पर एक आम राय कायम करने में सफलता मिली।

गुट-निरपेक्षता की नीति, उसका विकास और आवश्यकता

श्री टी. एन. कौल ने अपने एक लेख में गुट-निरपेक्षता के जन्म और विकास की रूपरेखा खींचते हुए इस बात की विवेचना की है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट-निरपेक्षता क्यों आवश्यक और उपयोगी है—

“यह सही है कि गुट-निरपेक्षता की नीति का जन्म द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हुआ, जब शीतयुद्ध ने विभिन्न देशों को वैचारिक और नैतिक दृष्टि से दो विरोधी गुटों में बाँट दिया था। भारत के प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, बर्मा के प्रधानमंत्री ऊ नू और मिस्र के राष्ट्रपति नसिर सादत नव-स्वतन्त्र देशों के महान् नेताओं ने यह निर्णय ही छोड़ अपनाई।

जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, गुट-निरपेक्षता की नीति अहिंसा, शान्ति और मंत्री पर आधारित हमारे स्वतन्त्रता-समर्प से उपजी थी। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो, घाना के राष्ट्रपति एन्क्रुमा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री भण्डारनायक, जांबिया के राष्ट्रपति काउंडा और तंजानिया के राष्ट्रपति न्युरेरे जैसे अन्य नेताओं ने नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नीति कह कर इसका समर्थन किया। कारण, इन देशों को शान्ति और आर्थिक विकास की तथा दोनों विरोधी गुटों में से किसी के भी खिलाफ न उलझने की जरूरत थी, ताकि वे आजादी के साथ अपना सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकें, जिसकी विदेशी शासन के दौरान घोर उपेक्षा हुई थी।

आरम्भ में गुट-निरपेक्षता की इस नीति को दोनों प्रतिस्पर्द्धा गुट शक्त की निगाह से देखने थे। चीन के माओत्से तुंग जैसे कमिपय समाजवादी नेता महसूस करते थे कि हर देश को इस या उन गुट की ओर झुकना ही होगा और कोई विचलता या तीमरा शस्ता नहीं है। अमेरिका के जॉन फास्टर डलेम गुट-निरपेक्षता का 'अनैतिक' कहते थे; मगर वह दौर गुजर गया और अधिकाधिक राष्ट्र गुट-निरपेक्ष दल में शामिल होते गए तथा गुट-निरपेक्षता की नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों के लिए उचित, व्यवहार्य और सम्मानपूर्ण नीति स्वीकार किया जाने लगा। जर्मनी-जर्मनी एशिया, मकोवा, कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के अधिकाधिक देश आजाद होते गए, स्पे-स्पे राष्ट्रमन्त्र में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या बढ़ती गई। राष्ट्रसंघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में गुट-निरपेक्ष दल की संख्या बल और नैतिक बल बढ़ता चला गया। दोनों गुट अब उसे रिश्ताने की कोशिश करने लगे; क्योंकि अब वे इसका भरोसा नहीं कर सकते थे कि राष्ट्रमन्त्र में उन्हें बहुमत मिल ही जाएगा।

गुट-निरपेक्षता सब विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे तथा उपनिवेशों के खारजे की समर्थक और नस्लभेद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरोधी है। समाजवादी गुट ने महसूस किया कि उनकी तथा गुट-निरपेक्ष दल की नीतियों में कुछ समानता है। उदाहरण के लिए रमभेद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के प्रश्नों पर और राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलनों के मामले में उसने गुट-निरपेक्ष दल की माँगों का समर्थन किया। अमेरिका के नेतृत्व में दूसरा गुट इन माँगों का विरोध करता रहा; मगर गुट-निरपेक्ष दल और मोविमन गुट मिलकर संस्था में उनसे बहुत ज्यादा हो जाते थे। गुट-निरपेक्ष देशों की संख्या 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन के समय 29 थी। 1964 के काहिरा सम्मेलन तक वह दुगुनी से ज्यादा हो गई और अब 100 के करीब है। राष्ट्रमन्त्र के भीतर और बाहर वह एक जबरदस्त नैतिक और राजनीतिक शक्ति है।

बक्त गुजरने के साथ, गुट-निरपेक्षता का औचित्य अधिकाधिक स्पष्ट होता गया और गुट-निरपेक्षता ने उपनिवेशवाद, रमवाद और साम्राज्यवाद के विरोध तक ही अपना ध्यान सीमित न रख कर उसे निःपक्षीकरण, उपनिवेशवाद तथा अविश्वसित देशों पर विरमिन देशों के आर्थिक बर्धन्व तक फैला दिया।

1970 वाले दशक में नई आलोचक यह दर्शाने बिसा करते थे कि अब चूँकि राष्ट्रीय के बीच तनाव-मुक्तता (देनॉउ) की स्पष्ट पतन उठी है, इसलिए अब गुट-निरपेक्षता का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। हाल की घटनाओं ने इस दर्शन को गहन निष्ठ कर दिखाया, क्योंकि दोनों गुटों के बीच तनाव-मुक्तता की स्पष्ट अब घट चली है और तनाव अब गीतमुद्ध बढ़ रहा है। यह दर्शन इसलिए भी गलत है कि जब तक नाटो और वारसा सन्धि जैसी सैनिक मंत्री-सन्धियाँ मौजूद हैं, तब तक सैनिक दृष्टि से गुट-निरपेक्षता आवश्यक बनी रहेगी।

यदि सबकी नव सैनिक मंत्री-सन्धियाँ लुप्त हो जाएँ—हालाँकि निश्चित भविष्य में इसकी कोई सम्भावना नहीं दी जाती—तो भी गुट-निरपेक्षता की आवश्यकता बनी रहेगी, ताकि विकासशील देशों के बीच बढ़ता हुआ आर्थिक अन्तर कम किया जा सके। आर्थिक दृष्टि से अधिक समुन्नत और सैनिक दृष्टि से तात्कालिक देश विकासशील देशों को अपने शिर्का में लाने की कोशिश जब तक करते रहेंगे, गुट-निरपेक्षता की जरूरत तब तक बनी ही रहेगी।

बेशक जब तमाम सैनिक मंत्री सन्धियाँ विलुप्त हो जाएँ, धनी और गरीब देशों का आर्थिक अन्तर मिट जाए और 'एक विश्व' का सपना साकार हो जाए, तब गुट-निरपेक्षता की नीति की आवश्यकता कम रह जाएगी। मगर यह तो बहुत दूर का सपना है। वैसे तब भी इसकी आवश्यकता बनी ही रहेगी कि प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्र अपनी अलग पहचान, संस्कृति और परम्परा के अनुसार अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यक्तित्व को बचाए रखे। यदि समस्त राष्ट्रों के लोग एक-में दिखने, एक-सी वेशभूषा पहनने और एक-सा बरताव करने लगे तो दुनिया बड़ी ही नीरस जगह बन जाएगी। दुनिया की एक-रूपता की नहीं, अपितु विविधता में एकता की आवश्यकता है। हर राष्ट्र को अपनी जनता की इच्छा के अनुसार अपनी जीवन-शैली चुनने और दूसरे देश के दब-दबे एवं धोस के बिना जीने की आजादी रहनी ही चाहिए।

यह आदर्श विश्व म्यिनि आसानी से लायी नहीं जा सकती। इसलिए यह और भी अधिक आवश्यक है कि गुट-निरपेक्ष देश के देश एक-दूसरे के निश्चित आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करें तथा अपने मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों को सम्पुर्ण करें और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप में मुक्त रहते हुए अपनी प्रगति एवं विकास के लिए एक-दूसरे के अनुभवों में समीक्षा करें। यह भी जरूरी है कि अधिक विविध देशों में व्यापार तथा समाधानों एवं उद्योग लक्ष्य आदि के स्थानान्तरण की अधिक प्रचलित व व्यापक शक्ति हस्तित करने के लिए वे अपनी सम्मिलित मौदेबाजी की ताकत बढ़ाएँ।

संवाद-प्रेम और सूचना क्षेत्र में भी विकासशील देशों पर विविध देशों की जबरदस्त गिरफ्त है। सूचना और संवाद-प्रेम के लगभग 80 प्रतिशत चैनलों पर पश्चिम का आधा दर्जन रेडियो-टेलीविजन एजेंसियों और समाचार-संस्थाओं का वर्चस्व है। ये विकासशील और गुट-निरपेक्ष देशों की स्थिति का बड़ा

हो तुड़ा-भुड़ा चित्र पेश करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रगति को सादर हो सभी दुनिया के सामने रखते हैं।

इसमें भी बुरी बात तो यह है कि प्रायः गुट-निरपेक्ष और विकामरत पक्षीनी राष्ट्रों के बीच परस्पर सीधे संवाद-प्रेषण के साधन नहीं हैं और उन्हें दूरवर्ती विद्वान् देशों की माफ़ी एक-दूसरे को संवाद भेजने पड़ते हैं। यह स्थिति सर्वथा असहनीय है और जगत्गत वक्त तक बनी रहने नहीं दी जा सकती। विकामरत गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की अपनी समाचार-संस्थाओं को एकजुट करना चाहिए, ताकि वे एक-दूसरे के समक्ष तथा बाहर की दुनिया के समक्ष अपनी तस्वीर सही रूप में पेश कर सकें। गुट-निरपेक्ष देशों के 'न्यूज़-ग्रुप' के रूप में एक दिशा में प्रयत्न तो शुरू किया गया है। मगर दुर्भाग्य से विकामरत देशों के अनेक राष्ट्रव्यापी प्रसिद्ध 'न्यूज़-ग्रुप' का पर्याप्त लाभ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अब भी मुट्ठी-भर विकसित देशों के रेडियो-टेलीविजन मण्डलों और समाचार-सेवाओं के प्रभाव में हैं।

युनेस्को ने सीन मैक्ग्राइड की अध्यक्षता में एक आयोग इन मामलों की जाँच के लिए बंटाया था। अक्टूबर, 1980 में वेनब्रेड में युनेस्को महामन्त्र के दिग्गज अधिवेशन में मैक्ग्राइड रिपोर्ट पर विचार किया गया। विभिन्न सरकारों की एक समिति भी युनेस्को ने गठित की है, जिसमें भारत को निम्नित किया है। एक तात्त्विकी मञ्जन इसके अध्यक्ष हैं और विश्व के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधि इनमें हैं। सूचना और संवाद-प्रेषण के क्षेत्र में मौजूदा अन्तुलन को कम करने के युनेस्को के इन प्रयत्नों के विरुद्ध यद्यपि चन्दनिहित स्वार्थ वाले, पश्चिमी प्रसिद्ध तथा समाचार-मण्डल हो-हन्ला मचा रहे हैं, तथापि इन दिशा में ठोस काम होने लगा है और जोर पकड़ रहा है।

विद्वान् और विकामरत दोनों प्रकार के देशों का हित इनमें है कि इन दिशा में वे सहयोग करें। इसने वे एक-दूसरे की सही तस्वीर देन और समझ पाएँगे, और व्यापार-व्यापार, नष्ट शुल्क और कोटारूनी प्रतिबन्ध, संसाधनों और तकनीकी के हस्तान्तरण की गरीबों आदि से सम्बन्धित समस्याओं को मुठभेड़ के बजाय मिन बँटकर बातचीत के जरिये सुलझाना सम्भव हो पाएगा।

आज दुनिया अर्थशास्त्रिक परस्पर-निर्भर होती जा रही है। दुनिया के एक कोने में अगर बुद्ध होना है तो उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता ही है। नाभिक्रीय बमों द्वारा विध्वंस का खतरा सारी मानव जाति के समक्ष मुँह बाँधे खड़ा है। अन्तराष्ट्रीय तनाव घटाना न्यूक्लीयर तथा दूसरे सब प्रकार के अस्त्रों का निःशस्त्रीकरण, अस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा को कम करना और इन प्रकार बने आर्थिक-साधनों का विकास के लिए चिन्तित होना हम सबके लिए एक-दूसरे की समस्याओं की अधिक गहरी समझ और विश्व के तमाम देशों के बीच अधिक आर्थिक-साधक और राजनीतिक सहयोग उत्पन्न आवश्यक है। इसके लिए संवाद-प्रेषण की वर्तमान विश्व-व्यवस्था (यानि कि अव्यवस्था!) को सुधारना जरूरी है। इन दिशा में ठोस कदम जितनी जल्दी उठाए जायें, उम्मेदारी दुनिया का उनता ही भया होगा।

राष्ट्रसंघ के सदस्यों में से दो-तिहाई के बराबर देश गुट-निरपेक्ष हैं, उन्हें इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

विकासरत देशों की आवादी दुनिया की दो-तिहाई आवादी से ज्यादा है और इनमें से आधे से ज्यादा देश गरीब हैं। इसलिए भूखग्रस्त और गरीब, आधी मानव-जाति के लिए शिक्षा, अच्छे गुजर-बसर और रोजगार की सुविधाएँ आदि प्राप्त करने के कदम तुल्य उठाने जरूरी हैं। अन्यथा धनी और निर्धन राष्ट्रों के बीच तथा एक ही देश के सम्पन्न और विपन्नों के बीच की खाई और चौड़ी होती जाएगी, जिससे सामाजिक-राजनीतिक तनाव एवं संघर्ष बढ़ेगा और विश्व की शान्ति, सुरक्षा और प्रगति के लिए खतरा उपस्थित हो जाएगा।

गुट-निरपेक्षता की अभिव्यक्ति : विभिन्न सम्मेलन

गुट-निरपेक्षता की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण हमें गुट-निरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों से मिलता है। गुट-निरपेक्ष देश कभी शिखर-सम्मेलनों का आयोजन करते हैं तो कभी विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का। हमसे चार लाभ होने हैं— (1) गुट-निरपेक्षता की लोकप्रियता में वृद्धि होती है, (2) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर गुट-निरपेक्ष देशों के दृष्टिकोण स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होते हैं, (3) गुट-निरपेक्ष देशों में पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि होती है, एवं (4) विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर गुट-निरपेक्ष देशों की आवाज को बल मिलता है।

प्रथम शिखर-सम्मेलन (बेलग्रेड).1961

सितम्बर, 1961 में बेलग्रेड में गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर-सम्मेलन हुआ जिसमें 25 देश सम्मिलित हुए। सम्मेलन में ज्वलन्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार किया गया और महाशक्तियों से अनुरोध किया गया कि शीनयुद्ध की उग्रता कम करें, पारस्परिक वार्ता द्वारा समस्याओं के समाधान ढूँढ़ें, निःशस्त्रीकरण की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ें और प्रत्यक्ष वार्ता करके परमाणु परीक्षण तथा शीनयुद्ध की समस्याओं को निबटाएँ। यह मत प्रकट किया गया कि विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि सभी देशों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाकर उन्नत अवस्था की ओर अग्रसर किया जाए। विज्ञप्ति में कहा गया कि सभी देशों को अपने ढंग से शासन-मंचालन की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा घरेलू मामलों में विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सदस्यों ने रंगभेद के नाम पर मनुष्य-मनुष्य में व्याप्त घृणा पर गंद व्यक्त किया और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की शर्तना की। विश्व में गैरनिर्वाच्य अड्डों की स्थापना पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें गमनाप्त करने की अपील की गई। सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि मसारा शान्ति की ओर तभी बढ़ सकता है जब सभी व्यवस्थाएँ और विचारधाराएँ एक-दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर परस्पर सहयोग करें और संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णयों को पूर्ण मान्यता देकर उसे मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो।

वेलप्रेड सम्मेलन में कुछ मतभेद भी उभरे। इण्डोनेशिया के डॉ. सुकार्णो ने उपनिवेशवाद को समकालीन विश्व की बुराइयों की जड़ बतलाया जबकि पं. नेहरू ने विश्व-शांति की स्थापना को मुख्य स्थान दिया।

द्वितीय शिखर-सम्मेलन (काहिरा), 1964

अक्तूबर, 1964 में काहिरा में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का दूसरा शिखर-सम्मेलन हुआ जिसमें 47 देशों ने भाग लिया। 11 देशों से पर्यवेक्षक भी सम्मिलित हुए। भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय शास्त्री ने विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए एक पाँच-गुनी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो इन प्रश्नों से सम्बन्धित था—(i) अणु निःशस्त्रीकरण, (ii) सीमा-विवादों का शान्तिपूर्वक हल, (iii) विदेशी प्रभुत्व, आक्रमण एवं तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों से मुक्ति, (iv) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा आर्थिक विकास, एवं (v) समुक्त राष्ट्रसंघ कार्यक्रम का समर्थन। भारत ने राष्ट्रों के आचार-संहिता सम्बन्धी एक दस सूत्री योजना भी प्रस्तुत की।

तृतीय शिखर-सम्मेलन (लुसाका), 1970

सितम्बर, 1970 में गुट-निरपेक्ष देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका में हुआ जिसमें 54 देशों ने भाग लिया। 9 पर्यवेक्षक सम्मिलित हुए। सम्मेलन के मुख्य विषयबिन्दु ये थे—(i) सम्मेलन ने विश्व के सम्पन्न और निर्धन देशों की खाई की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आर्थिक तथा सुरक्षात्मक उपायों पर बल दिया। (ii) पुराने उपनिवेशवाद के साथ-साथ नव-उपनिवेशवाद की भी आलोचना की गई। (iii) सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष दलों का स्थायी संगठन बनाने और उनका कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे गुट-निरपेक्षता की भावना को ठेस पहुँचने की सम्भावना थी। भारत के बड़े विरोध के कारण ऐसा संगठन नहीं बन पाया।

जाजेंटाउन सम्मेलन, अगस्त 1972

गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का एक चार दिवसीय सम्मेलन जाजेंटाउन में हुआ व एक घोषणा का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें निम्नलिखित मुख्य बातें थी—

1. गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास पर बल दिया गया।
2. हिन्द-चीन, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में संधियों पर चिन्ता प्रकट की गई।
3. यह स्पष्ट किया गया कि समुक्त राष्ट्र महासभा को हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र रखने की घोषणा पर अमल किया जाए।
4. दक्षिण वियतनाम की अस्थायी कान्तिकारी सरकार की योजना का और पेकिंग स्थित कम्बोडिया की सिहानुक सरकार के पाँच सूत्री प्रस्ताव का समर्थन किया गया। यह भाग भी गई कि अमेरिकी फौजों को वियतनाम से शीघ्र वापस चला जाना चाहिए।

सम्मेलन में भारत सहित 58 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन की आधिकारिक समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों को आत्म-निर्भरता पर जोर देना चाहिए और द्वि-पक्षीय व्यापार में यथासम्भव राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करना चाहिए। एक प्रस्ताव में अमेरिका की आक्रमणकारी नीति और हिन्द-चीन में युद्ध-विस्तार की कड़े शब्दों में निन्दा की गई।

चतुर्थ शिखर-सम्मेलन (अल्जीरिया), 1973

सितम्बर, 1973 में 4 से 8 तारीख तक गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का अल्जीरिया में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 76 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में लीबिया और अल्जीरिया के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया कि गुट-निरपेक्षता को एक नई परिभाषा दी जाए और गुट-निरपेक्ष देशों के लिए नया विधान बनाया जाए। घोषणा-पत्र में सुझाव दिया गया कि तटस्थ राष्ट्र कम्बोडिया के राजकुमार मिहानुर की निर्वाचित सरकार को मान्यता दे, मिस्र, सीरिया तथा जोर्डन के इजराइल अधिकृत क्षेत्रों की मुक्ति के लिए राजनयिक सहयोग दें; वियतनाम की अस्थायी अन्तिमकारी सरकार को भी राजनयिक सहयोग दें तथा अफ्रीकी मुक्ति आन्दोलनों को सहयोग दें। श्रीमती गान्धी ने कहा कि कुछ बड़े राष्ट्रों द्वारा दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयत्नों का विरोध किया जाना चाहिए। रूस अमेरिका के बीच सम्बन्ध-सुधार का स्वागत किया गया पर साथ ही यह भी कहा गया कि सम्बन्ध सुधार से होने वाले लाभ सभी राष्ट्रों में समान रूप से बँटने चाहिए अर्थात् बड़े राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों के शोषण के नये रूपों का विनाश नहीं होना चाहिए।

अल्जीयर्स सम्मेलन, 1974

अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में 17 गुट-निरपेक्ष देशों के विदेशमन्त्रियों का तीन दिवसीय सम्मेलन (20 से 22 मार्च, 1974) हुआ। सम्मेलन में हिन्दमहासागर में अमेरिका द्वारा डियागो गार्सिया को नौ सैनिक अड्डा बनाने के निश्चय की आलोचना की गई। तेल उत्पादक देशों से अपील की गई कि वे विकासशील देशों के प्रति उदार रव्य अपनाएँ। गुयाना, श्रीलंका, नेपाल और माइबेरिया का अध्ययन-गुट बनाया गया जिसे तेल-उत्पादक देशों के गठन के साथ परस्पर सहयोग और तात्कालिक द्वारा समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार-विमर्श करने का कार्य सौंपा गया। एक अन्तर्संरकारी गुट का भी गठन किया गया जिस पर यह भार डाला गया कि वह विभिन्न देशों में पैदा होने वाले कच्चे तेल का जायजा ले और बड़े देशों के साथ कच्चे तेल के बारे में समझौता करने की दिशा में अग्रणी सहाय दे।

मार्च 1975 में हवाना-सम्मेलन

मार्च, 1975 में 17 गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन हवाना में हुआ। सम्मेलन में हिन्द महासागर में ब्रिटेन और अमेरिका की उपस्थिति

की निन्दा की गई। महाशक्तियों के इस ग्व को हिन्द महासागरीय क्षेत्र के राज्यों की स्वतन्त्रता और क्षेत्रीय अखण्डता पर आपात माना गया। संयुक्त राष्ट्रगण के उम प्रस्ताव का समर्थन किया गया जिसमें हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाने की बात कही गई थी। अन्य प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श हुआ, जैसे—तनाव में शिथिलता, पश्चिमी एशिया में उपनिवेशों की समाप्ति, हिन्द-चीन तथा साइप्रस। किलिस्तीन के प्रश्न पर अलग से एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें माँग की गई कि गुट-निरपेक्ष देश किलिस्तीन में ग्यामसगत तथा स्थायी शान्ति की स्थापना प्रयासों में प्रभावी, ठोस तथा खुलकर योगदान दें। इस विश्वास की पुन. पुष्टि की गई कि विश्व की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि समस्त विश्व इसके लिए ऐसे पारस्परिक सहयोग के कार्य करे जो नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी घोषणा और कार्यक्रम के अनुसार सभी देशों की समानता और सम्मान पर आधारित हो।

अगस्त 1975 में लीमा सम्मेलन

गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन 25 से 30 अगस्त, 1975 तक लीमा (पीरू) में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन ने 'परस्पर सहायता एवं एकता का लीमा-कार्यक्रम' शीर्षक से एक घोषणा प्रसारित की। घोषणा के आर्थिक खण्ड में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की एकता एवं बन्धुत्व को सुदृढ़ बनाने की एक योजना भी शामिल थी। सम्मेलन में विशिष्ट राजनीतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इन सम्मेलन में 82 सदस्य देशों तथा कई पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि कुछ गुटबद्ध देशों ने भी इसमें पर्यवेक्षक तथा अनिविध के रूप में भाग लेने में रुचि प्रदर्शित की। राजनीतिक प्रश्नों के अन्तर्गत मध्यपूर्व तथा किलिस्तीन, साइप्रस, इण्डोचीन और हिन्द महासागर के बारे में विचार-विमर्श हुआ। इण्डोचीन के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा एक स्वैच्छिक एकता निधि भ्यापित करने का निर्णय किया गया। सम्मेलन में हिन्दमहासागर पर एक अलग से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें इस विषय से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को दोहराया गया। सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक बोप की स्थापना का अनुमोदन किया। बोप की सदस्यता के लिए समान चन्दा 5,00,000 डॉलर निश्चिन्त किया गया। सम्मेलन ने कच्चे माल तथा विकासशील देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादनों के सुरक्षित भण्डार की वित्तीय व्यवस्था के लिए विशेष निधि की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तर्सरकारी विशेषज्ञ दल को समन्वित का अन्तिम प्रारूप तैयार करने के लिए प्रविकृत किया। सामूहिक गन्धार माधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की प्रेस-एजेन्सियों का एक त्रिपक्ष स्थापित करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों से परामर्श करने के बाद भारत ने एक प्रस्ताव रखा जिसे सम्मेलन ने स्वीकृत कर लिया।

गुट-निरपेक्ष देशों का मन्त्रिमण्डलीय सम्मेलन, जुलाई 1976

दिल्ली में 8-13 जुलाई को आयोजित गुट निरपेक्ष देशों का मन्त्रिमण्डलीय सम्मेलन इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था कि उसमें ऐसी समाचार एजेंसी के गठन पर विचार-विमर्श हुआ जो इन देशों की वास्तविक आवश्यकताओं व उपलब्धियों को केन्द्र-बिन्दु मानकर समाचारों का सग्रह और आदान-प्रदान करेगी। उसके माध्यम से न केवल पश्चिमी देशों की समाचार एजेंसियों पर आश्रित रहने की स्थिति खत्म हो जाएगी, बल्कि एक तटस्थ और पूर्वाग्रहमुक्त दृष्टि से काम करने के परिणामस्वरूप इन देशों का वास्तविक स्वरूप भी दुनिया के समक्ष लाया जा सकेगा। श्रीमती गांधी ने गुट-निरपेक्ष देशों और भूतपूर्व शासकों के बीच के असमान सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते की भी चर्चा की।

कोलम्बो में पाँचवाँ निर्गुट शिखर-सम्मेलन, अगस्त 1976

गुट-निरपेक्ष देशों का पाँचवाँ ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में 16 से 19 अगस्त, 1976 तक हुआ। श्रीमती भण्डारनायके सम्मेलन की अध्यक्षता निर्वहण हुई। सम्मेलन की सम्पूर्ण कार्यवाही के महत्वपूर्ण बिन्दु ये थे—

1. श्रीमती भण्डारनायके ने घोषणा की—“गुट निरपेक्ष देशों का सघर्ष किसी भी राष्ट्र अथवा समुदाय के विरुद्ध न होकर अन्याय, असहनशीलता, असमानता तथा हस्तक्षेप और चोचराहट के विरुद्ध है। शान्ति सब देशों का अधिकार है, इसलिए इसका दायित्व भी सब पर होना चाहिए।”

2. श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा—“सम्मेलन को अधिक न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण का संदेश प्रसारित करना चाहिए।” उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने सदैव अपनी कथनी और करनी में स्वतन्त्रता, न्याय, समता तथा सहयोग का पक्ष लिया है। भारत ने उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया है। श्रीमती गांधी ने सदस्य देशों से एकजुट होकर शान्ति की रक्षापत्ति सुदृढ़ करने की अपील की।

3. संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव डा. कुर्त वाल्डहीम ने कहा—गुट-निरपेक्ष देशों का कोलम्बो सम्मेलन राष्ट्रसंघ के कार्य और विश्व शान्ति तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

4. श्रीमती भण्डारनायके ने निर्गुट देशों की नयी अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए आह्वान किया और इसकी कुछ रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि निर्गुट राष्ट्रा को (1) एक नयी मुद्रा का प्रचलन करना चाहिए जिसकी पुश्त पर विकासशील देशों की अपरिमित आर्थिक शक्ति हो और साथ ही (2) तीसरी दुनिया के लिए एक व्यापारिक बैंक स्थापित करना चाहिए। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के सघर्ष में हम अपने निज की वित्तीय और मौद्रिक प्रणालियों का गठन करना चाहिए। श्रीमती भण्डारनायके का एक मुद्दा यह था कि तेल, ताम्बा, बाक्साइट और यूरेनियम आदि महत्वपूर्ण वस्त्रों के लिए उत्पादक एगोमिशन स्थापित की जाएँ ताकि विकासशील देश इन वस्तुओं के लिए उचित भूख प्राप्त कर सकें। यदि निर्गुट

देशों की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और व्यापारिक बैंक स्वतन्त्र रूप से स्थापित हो जाए तो लन्दन, पेरिस, जूरिख और न्यूयार्क का आज वित्तीय दृष्टि से जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व है, वह नहीं रह पाएगा। यदि सभी निर्गुट देशों की आर्थिक शक्ति मंगठित हो जाए तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और विकसित देशों की पराधीनता से उन्हें मुक्ति मिल सकती है।

5. निर्गुट देशों के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत आर्थिक घोषणापत्र में नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया। इस घोषणापत्र के प्रारूप में भारत के नई महत्त्वपूर्ण सुझावों का समावेश हुआ। घोषणापत्र में कहा गया—

(क) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन तथा पुनर्गठन किए बिना सारी दुनिया, खानकर विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं का समाधान असम्भव है। समूचा विश्व-समुदाय आज एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की खोज करने पर विवश हुआ है जो सामान्य श्रेयर, सार्वभौम समानता, परस्पर-निर्भरता, समान हितों और सहयोग पर आधारित हो।

(ख) बहु-उद्देशीय निगम अपने निजी लाभ के लिए विकासशील देशों के माधनों का शोषण कर उनकी अर्थ व्यवस्था को विह्वल करते हैं तथा इन देशों की सार्वभौमिकता का और आत्म-निर्णय के अधिकारों का उन्मूलन करते हैं। ये निगम बहुधा धूम देने और भ्रष्टाचार के अन्य कुत्सित तरीके अपनाते हैं तथा विकासशील देशों को औद्योगिक देशों के अधीन बनाते हैं।

(ग) यदि बड़ी सैनिक शक्तियाँ निःशस्त्रीकरण की दिशा में काम करें तथा अपने माधनों का एक बड़ा भाग विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति की सुधारने में व्यय करें तो विकासशील देशों की काफी जरूरतें पूरी हो सकती हैं और निरुद्ध भविष्य में ही विकसित तथा विकासशील देशों के बीच की खाई पाटी जा सकती है।

(घ) विकसित देशों से ऐसे कदम उठाने की अपील की गयी जिससे वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बल मिले और अन्ततः नयी आर्थिक व्यवस्था विकसित हो।

6. घोषणापत्र में 'शब्द को कोई स्थान न देकर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी' वाक्यांश का प्रयोग किया गया।

7. सम्मेलन हम निष्कर्ष पर पहुँचा कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सार्थकता तथा विश्व सन्तुष्टि में इसकी उत्तरोत्तर बढ़ती भूमिका के कारण इन देशों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे गुट-निरपेक्षता के मूल स्वरूप के संरक्षण के लिए सन्तुष्ट जागरूक रहें तथा इसके मिद्धान्तों और नीतियों में अपनी मट्ट घास्या रखने हुए इस आन्दोलन की एकजुटता तथा अखण्डता की रक्षा के लिए इसके निर्णयों का पालन करें। सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष देशों के बीच घनिष्ठ एकता का आह्वान किया। गुट-निरपेक्ष देशों की समूचे विश्व की प्रगतिशील तथा आन्तिमिष शक्तियों के साथ अपना सहयोग जारी रखने पर जोर दिया गया।

8. बंगलादेश ने सम्मेलन में पंगा के पानी के बँटवारे का सुझाव उठाया और भारत पर अनेक अनुचित आरोप किए। श्रीमती गांधी ने सम्मेलन में द्विपक्षीय मामले न उठाने पर अधिक जोर दिया क्योंकि इससे सामुदायिक उद्देश्य दृष्टि से लाभ हो सकते हैं।

कोलम्बो के इस पाँचवें निर्गुट शिखर-सम्मेलन में 40 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष तथा शानवाध्यक्षों ने भाग लिया। माजदीप को निर्गुट राष्ट्र संगठन का पूर्ण सदस्य बना लिया गया। इस प्रकार यह देश संगठन का 86वाँ सदस्य देश बना। शिखर-सम्मेलन में निर्गुट देशों का जो आधिकार्यक्रम स्वीकार किया उसमें प्रतीत की गयी कि आधिकार और सामाजिक विकास के लिए 'एकता-कोष' स्थापित कर 1976 के अन्त तक उनको शुरू कर दिया जाए। सम्मेलन के 25 सदस्यीय ब्यूरो में भारत, श्रीलंका, ईराक, सीरिया, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा तथा इण्डोनेशिया आम सहमति के आधार पर सदस्य चुन लिए गए। अफगानिस्तान और बंगलादेश ब्यूरो में स्थान पाने के लिए अपने दावों पर अड़े रहे और तब यह निर्णय किया गया कि तीन वर्ष के कार्यकाल में शुरू के डेढ़ वर्ष बंगलादेश और शेष डेढ़ वर्ष अफगानिस्तान सदस्यता ग्रहण करेगा।

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन हवाना 1978

गुट-निरपेक्ष देशों के सम्बन्ध ब्यूरो के मई 1978 के हवाना (क्यूबा) सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी निःशस्त्रीकरण पर गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना का विचार। हवाना सम्मेलन में निःशस्त्रीकरण पर व्यापक रूप से विचार किया गया। हवाना सम्मेलन ने महासभा से अनुरोध किया कि हथियारों की होड़ समाप्त करने के लिए यह निश्चित कदम उठाए। सम्मेलन ने एक दस्तावेज स्वीकृत किया। जिसमें दो खण्ड थे—राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक खण्ड गुट-निरपेक्षता की भूमिका और परिभाषा, गुट-निरपेक्ष देशों के बीच एकता और एकजुटता की आवश्यकता और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गुट-निरपेक्ष देशों के मनो की पुनः अभिपुष्टि से सम्बन्धित थे। भारत ने गुट-निरपेक्ष देशों के मूचना और प्रसारण संगठनों के उकाता, सारजेजी और हवाना में हुए तीनों सम्मेलनों के प्रतिवेदनों और मिफारिशों का अनुमोदन भी किया। आर्थिक खण्ड के अन्तर्गत वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति का विश्लेषण, विवर्धित तथा विकासशील देशों के बीच चल रही वार्ता के परिणामों का मूल्यांकन, तृतीय विकास दशक के लिए कार्य नीति का निर्धारण करने वाले तत्त्व और गुट-निरपेक्ष तथा विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए बने कोयम्बों विधानीय के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा शामिल थे।

भारत के विदेश राज्यमन्त्री समरेन्दु कृष्ण ने गुट-निरपेक्ष देशों की स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि वे द्विपक्षीय आपसी मतभेद दूर नहीं करते हैं तो बाहर के देश उनकी कमजोरी का पानदा उठाकर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। उनका यह भी कहना था कि हमें वास्तविक क्षयों में सदस्यता का गानन करना है।

यह तटस्थता उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इसके द्वारा संसार को आभास मिलना चाहिए कि हम सच्चे अर्थों में गुटवन्दी की राजनीति से बिल्कुल ग्रहण हैं। अनेक विदेश मन्त्रियों और शासनाध्यक्षों ने गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सीमा सम्बन्धी विवादों पर चिन्ता व्यक्त की। सभी देशों के प्रतिनिधियों ने इन विवादों को आपसी बातचीत द्वारा हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इण्डोनेशिया के विदेश मन्त्री ने कहा कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को देशों के द्विपक्षीय मामलों में दखल नहीं देना चाहिए बल्कि समान समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सम्मेलन में इजरायल की कड़ी निन्दा की गयी। उसे विश्व युद्ध भड़काने वाले देश की सजा दी गयी। दुनिया के देशों से अधिकाधिक अस्त्र प्राप्त करने के लिए भी इजरायल को बुरा भला कहा गया और सम्मेलन में भाग लेने वाले देश इस बात से भी नाराज थे कि इजरायल, दक्षिण अफ्रीका, खाटेमाला और दक्षिण अमेरिका में हथियारों की बिक्री को बढ़ावा दे रहा है। पवित्रभूमिवासी नीति को लेकर अमेरिका की काफी निन्दा की गयी।

वेलग्रेड गुट-निरपेक्ष सम्मेलन, जुलाई 1978

गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन 25 से 29 जुलाई 1978 तक हुआ जिसमें भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। इस सम्मेलन में पाकिस्तान तथा सानमारिनो की प्रतिनिधि देशों के रूप में शामिल किया गया। भारत ने पाकिस्तान का अनिविध के रूप में स्वागत करते हुए यह आशा व्यक्त की कि यह सैनिक सन्धि-समझौते से स्वयं को अलग रखने का प्रयत्न करेगा। भारत राजनीतिक समिति का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। भारतीय विदेशमन्त्री ने गुट निरपेक्षता के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति भारत की पूर्ण वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत इन सिद्धान्तों का निष्ठापूर्वक पालन करके ही महाशक्तियों में से प्रत्येक के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारने में समर्थ हो पाया है और ऐसा करते हुए न वह उनके आपसी मतभेदों में पड़ा और न ही उन मामलों में फँसा है जो अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को बढ़ाते हैं। साथ ही गुट-निरपेक्षता के दर्शन से अनुप्रेरित होकर भारत ने सफलतापूर्वक अपनी पुरानी और जटिल समस्याओं का हल तलाश किया है और अपने पड़ोसी देशों के साथ सद्भाव और सहयोग का सेतु निर्माण किया है। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि द्विपक्षीय समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के दृढ़ निश्चय से वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे यह आन्दोलन संसार की बड़ी-बड़ी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान में एक निश्चित भूमिका का निर्वाह कर सक्ता है। सम्मेलन ने उन गुट-निरपेक्ष देशों से एक विशेष अपील की जो द्विपक्षीय झगड़ों में उलझे हुए थे कि वे बातचीत के द्वारा शान्तिपूर्ण समझौता करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करें। भारत के इस दायें को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ कि यदि देश ईमानदारी से गुट-निरपेक्ष रहे तो बाहर या भीतर से हुआ कोई भी प्रयास आन्दोलन को न तो कमजोर कर सकता है और न अपने पथ से विचलित ही।

सम्मेलन ने एक घोषणा पत्र स्वीकार किया जिसके दो भाग थे और एक पृथक् खण्ड था जिसमें आर्थिक सहयोग विषयक कोलम्बो त्रियाशील कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सुरक्षा की गई थी। घोषणा के राजनीति विषयक भाग में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मामलों और साथ ही उन मामलों पर गुट-निरपेक्ष देशों का संयुक्त रवैया परिलक्षित हुआ जिनका गुट-निरपेक्ष आन्दोलन सामना कर रहा है। घोषणा का एक नया स्वरूप मानव अधिकार सम्बन्धी एक नया खण्ड था जिसमें भारत की ही पहल पर विश्व समुदाय के लिए इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया था कि वह मानव अधिकारों के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाएँ। घोषणापत्र में विश्व में तनाव के लिए बड़ी शक्तियों के विगड़ते सम्बन्ध, हथियारों की दौड़ और नए प्रकार के प्रभुत्ववाद को जिम्मेदार ठहराया गया। अफ्रीका में विदेशी सैनिक झुठों और गैर-अफ्रीकी ताकतों के साथ हुए समझौतों की भी निन्दा की गई और अफ्रीका को युद्ध क्षेत्र या शीतयुद्ध का अखाड़ा बनाए जाने के प्रयासों का विरोध किया गया। अफ्रीकी एकता संगठन के अन्तर्गत एक ऐसी अफ्रीकी सेना के गठन का समर्थन किया गया जो उस महाद्वीप की सुरक्षा और एकता बनाए रख सके। गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसियों के गठन की भूमिका पर बल दिया गया। हिन्दमहासागर क्षेत्र में स्थित विदेशी बड़े सैनिक झुठे समाप्त किए जाने की माँग की गई। अफ्रीका के जातिवादी शासकों को आर्थिक और सैनिक सहायता देने वालों की निन्दा की गई। पूर्वी तिमारे के आत्म-निर्णय के अधिकार का समर्थन किया गया। इजरायल पर परमाणु प्रतिक्रिया लगाने की माँग की गई और आक्रमण, कब्जा और विस्तार की नीतियों की निन्दा की गई। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को सभी गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा राजनयिक दर्जा देने का प्रस्ताव है, साइप्रस के सभी विदेशी सैनिकों को हटाने की माँग की गई और निःशस्त्रीकरण समझौते में सभी देशों के भाग लेने की ज़रूरत पर जोर दिया गया।

अनियेय देश यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने कहा कि "गुट-निरपेक्ष जगत् के प्रति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, विशेषकर अफ्रीका में नए प्रकार की औपनिवेशिक उपस्थिति या गुट-निर्भरता, विदेशी प्रभाव तथा प्रभुत्व" का प्रतिरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ही गुट-निरपेक्षता के उद्देश्यों को भी परिभाषित कर दिया—“यह नीति साम्राज्यवाद, नव-औपनिवेशवाद, नस्लवाद और अन्य सभी प्रकार के विदेशी प्रभुत्व तथा जीपण का विरोध करनी है। सत्ता राजनीति, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभुत्ववाद और सब तरह के बाह्य हस्तक्षेप तथा निर्भरता के विरुद्ध है।”

सम्मेलन की समाप्ति पर प्रसारित 80 पृष्ठीय विज्ञप्ति सर्वसम्मत नम, वैचारिक तथा सैद्धान्तिक स्तर पर पूर्णतया विभाजित सदस्यों को घेन-बेन प्रकारेण एकरा सूत्र में बाँधे रखने का प्रयास अपिष्ट थी। वित्तिपति में यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठा था कि गुट-निरपेक्षता में आस्थाहीन देशों को आविर कब तक आगोपित एकरा के छद्म में एक मंच पर इकट्ठा रखा जा सकेगा।

मोजाम्बिक का विशेष सम्मेलन, जनवरी-फरवरी 1979

दक्षिण अफ्रीका में हुई घटनाओं पर विचार करने के लिए मापूतो (मोजाम्बिक) में 28 जनवरी से 2 फरवरी 1979 तक गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो के विदेश मंत्रियों का एक विशेष सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की समालोचिका पर स्वीकृत एक घोषणा में ब्यूरो ने गुट-निरपेक्ष देशों की पिछली बैठकों और समुक्त राष्ट्रमंडल में किए गए निर्णयों और मिफागियों को दोहराया और आगे कुछ और कार्यवाही करने की मांग की गई—

- (क) दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संघर्ष के लिए राजनीतिक, राजनयिक सैनिक और विद्वान सभी प्रकार के समर्थन में वृद्धि की जाए।
- (ख) दक्षिणी अफ्रीका पर पूर्ण और प्रभावकारी सैन्य-प्रतिबन्ध लगाया जाए।
- (ग) भाड़े के विदेशी सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पारगमन और वित्तदान पर रोक लगायी जाए।
- (घ) दंग प्रेमी मोर्चे (जिम्बाब्वे) को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाए।

कोलम्बो में गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की बैठक, जून 1979

भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 से 9 जून, 1979 तक कोलम्बो में आयोजित गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया। कम्बोडिया का प्रतिनिधित्व और मिस्र को शामिल होने के मवाज, ये दो ऐसे राजनीतिक विषय थे जो इस सम्मेलन पर छाए रहे। ब्यूरो की बैठकों के विषय में निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए ब्यूरो के गैर-सदस्यों के बीच बढ़ती हुई इच्छा ने इसमें एक तीसरा आयाम जोड़ दिया। इसके फलस्वरूप इस ब्यूरो के 23 सदस्यों की उपस्थिति के अतिरिक्त इस बैठक में इस आन्दोलन के 52 सदस्यों, 9 प्रेक्षकों/अतिथियों तथा 12 अन्तर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सभठनों ने भाग लिया।

भारत ने इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाई। कम्बोडिया के प्रतिनिधित्व तथा मिस्र के भाग लेने से सम्बन्धित अत्यन्त विवादास्पद मामलों के बारे में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने समझौते का समाधान ढूँढने की दिशा में कार्य किया ताकि इन आन्दोलन का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने की ओर से न हटे।

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन, हवाना (सितम्बर 1979)

गुट-निरपेक्ष देशों का छठा विश्व-सम्मेलन 3 से 9 सितम्बर, 1979 तक हवाना में हुआ। यह पहला मौका था जबकि ऐसा सम्मेलन एक सेटित अमेरिका के किसी देश में हुआ। सम्मेलन में 54 राजवाध्यक्ष/शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। उनकी सदस्य संख्या 94 हो गई जिसमें 20 देश और सभठनों के प्रेक्षक थे तथा 18 देश अतिथि थे। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री पयाम

नन्दन मिश्र ने किया। भारत को सम्मेलन का एक उपाध्यक्ष चुना गया और इसकी 36% सदस्यों के विस्तृत समन्वय ब्यूरो के लिए पुनः निर्वाचित किया गया।

यह सम्मेलन एक प्रच्छन्न तनाव के वातावरण में हुआ। कम्पूचिया (कम्बोडिया) का प्रश्न, मिस्त्र-इजरायल सन्धि तथा पश्चिम सहारा का प्रश्न जैसे फूट डालने वाले गम्भीर मसले ही नहीं थे बल्कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मूलभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को धनाए रखने तथा उसकी भावी भूमिका और निर्देश के बारे में यदि चिन्ता नहीं तो कम से कम एक अनिश्चितता भी बनी हुई थी। इस सम्बन्ध में मतभेद हो गया कि कम्बोडिया का स्थान खाली रखा जाए क्योंकि गुट-निरपेक्ष समुदाय के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह वर्तमान स्थिति में किसी एक या दूसरे प्रतिनिधि मण्डल के पक्ष में कोई निर्णय ले सके। मिस्त्र-इजरायल सन्धियों की तीव्र आलोचना की गई और इन सन्धियों के प्रति अस्वीकृति तथा निन्दा अभिव्यक्त करते हुए एक कठोर संकल्प पारित किया गया। मिस्त्र को निलम्बित करने की माँग के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सका और यह सहमति हुई कि इस सवाल को आगे विचार के लिए समन्वय ब्यूरो को भेज दिया जाए। इस बारे में सहमति थी कि विश्व शांति और स्थायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के संवर्द्धन के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन एक रचनात्मक, स्वतन्त्र तथा महत्वपूर्ण घटक है।

भारत ने अपनी इस धारणा को दोहराया कि गुट-निरपेक्ष सम्मेलनों को फूट डालने वाले गुटों और द्विपक्षीय विवादों से बचना चाहिए और इसके बदले में ऐसे व्यापक उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो गुट-निरपेक्ष देशों को एक-दूसरे के निकट लाएँ। यह आवश्यक है कि इस आन्दोलन की एकता को सुरक्षित और सुदृढ़ किया जाए तथा इसकी सक्रियतात्मक वारंशता को अधिक जीवन्तता प्रदान की जाए।

इस सम्मेलन द्वारा पारित अन्तिम घोषणापत्र में एक राजनीतिक तथा आर्थिक खण्ड और कार्यवाही सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल थे। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्राप्ति के लिए नवीनीकृत और तीव्र प्रयत्नों के किए जाने की माँग को दोहराया गया। विकासशील देशों की अत्यावश्यक आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सभी देशों में परस्पर बातचीत का एक नया दौर शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। तीसरे समुक्त राष्ट्र विकास दशाब्दी (नवें दशक) के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति तैयार करने के महत्त्व पर बल दिया गया। कच्चे माल तथा ऊर्जा जैसे अतिशय महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भारत ओपेक देशों की सहायता और सहयोग से एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने में सफल हुआ जिसमें गुट-निरपेक्ष देशों के बीच उनकी अपनी सामूहिक निर्भरता सुदृढ़ करने में परस्पर सहयोग करने के मार्ग-निर्देशन सिद्धान्त तय किए गए। एक महत्वपूर्ण निर्णय का सम्बन्ध गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसियों के पूल के कार्यबन्धनों तथा सूचना के क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष देशों के अन्य कार्यबन्धनों में था। सम्मेलन ने इस पूल के कार्य निष्पादन की प्रगति की और इन पूल में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सदस्यों से कहा।

विदेश मन्त्रियों का नई दिल्ली सम्मेलन, फरवरी 1981

गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन 9 से 13 फरवरी, 1981 तक नई दिल्ली में हुआ। 91 देशों और दो मुख्य आन्दोलनों के अनिरिक्त 15 प्रेक्षक प्रतिनिधि मण्डलों ने और 22 अनिवि-प्रतिनिधि मण्डलों ने इसमें भाग लिया। 9 फरवरी, 1981 को उद्घाटन अधिवेशन में सम्मेलन को भारत की प्रधान मन्त्री का मुख्य भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। 1961 में बेलग्राड में सम्पन्न गुट-निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन की बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 11 फरवरी को एक विशेष स्मारक अधिवेशन हुआ। इस स्मारक अधिवेशन को प्रधानमन्त्री ने सम्बोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता विदेश मन्त्री ने की। नई दिल्ली सम्मेलन के सिलसिले में कुछ निहित क्षेत्रों में असाधारण अटकलें लगाई जा रही थी और गुट-निरपेक्ष देशों के इस आन्दोलन की वैधता पर ही उगमी उठायी जा रही थी। कुछ आलोचकों ने यह भविष्यवाणी तक की कि इस आन्दोलन की एकता में ही दरार पड़ जाएगी जिसके फलस्वरूप इसकी शक्ति और इसकी जीवन्तता क्षीण होगी। इस प्रकार के सारे अनुमान और अटकलें पूरी तरह निराधार सिद्ध हुईं। इस सम्मेलन की सफलता का सुनिश्चय करने के लिए भारत ने कई गुट-निरपेक्ष देशों के साथ सम्मेलन से पूर्व व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया। इन विचार-विमर्शों से एक अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिली तथा विशिष्ट मामलों पर और द्विपक्षीय मसलों के अतिरिक्त द्विपक्षीय समस्याओं पर ही समुचा ध्यान केन्द्रित कर देने के प्रयत्नों को रोकने में भी मदद मिली। अन्ततः यह सम्मेलन एक समरस भावना के साथ सम्पन्न हुआ और इसमें नई दिल्ली घोषणा स्वीकार की गई, जिसमें आज की सभी ज्वलन्त समस्याओं को शामिल किया गया है। यह घोषणा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका, गुट-निरपेक्षता की नीति, सभी राज्यों की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थिति मजबूत करने तथा सार्वभौम तनाव-अस्थिरता और वास्तविक निःशस्त्रीकरण की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक थी। इसने उपनिवेशवाद, जातिवाद तथा विदेशी आक्रमण और हस्तक्षेप तथा दखलन्दाजी के सभी रूपों के विरुद्ध संघर्षों को मजबूत किया।

आर्थिक क्षेत्र में सम्मेलन ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि इस सिलसिले में यथाशीघ्र विषयव्यापी वार्ता शुरू होनी चाहिए। ऊर्जा के महत्वपूर्ण मसले पर सम्मेलन का यह विचार था कि इसका आयात करने वाले गुट-निरपेक्ष और दूसरे विकासशील देशों को प्राथमिक आधार पर तथा किसी भी देश के प्रति कोई पूर्वाग्रह न रखते हुए मुद्रा की सन्तुष्टि के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। विकासशील देशों में परस्पर आर्थिक सहयोग के महत्त्व पर बल देते हुए सम्मेलन में इन बातों पर सहमति हुई कि काराकस के आगामी उच्च-स्तरीय सम्मेलन में सहयोग के समदयक ढोस, कार्यन्मुखता और सहमत तरीके, परियोजनाएँ और अव्यवस्था स्वीकार किए जाने चाहिए।

नई दिल्ली सम्मेलन के परिणामस्वरूप गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन की एकता और एक-जुटता काफी मजबूत हुई। यही वजह थी कि जिन मसलों पर गुट-निरपेक्ष देशों में मनभेद भी था उनमें भी एक आम राय कायम करने में सफलता मिली। सम्मेलन में भारत की रचनात्मक भूमिका और उसके प्रयासों की प्रशंसा की गई और इस बात की भी सराहना की गई कि इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत ने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन किया।

एक गुट-निरपेक्ष देश के रूप में भारत (India as a Non-aligned Country)

टी. एन. कौल ने लिखा है—“अगर पिछले वर्षों पर दृष्टिपात किया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत द्वारा निभायी गई भूमिका की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब हम इस बात पर ध्यान दें कि स्वाधीनता के समय भारत आज की अपेक्षा संसार की शक्ति-राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका भूना करने की कम क्षमता रखता था। लेकिन भय और अविश्वास, शक्ति-सन्तुलन, प्रभाव-क्षेत्र, शीतयुद्ध और सैनिक सन्धियों वाले तरफालीन विश्व में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति अपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण से एक नया बातावरण पैदा किया। भारत ने अपने भाग्य-निर्माण या ऐसे ही किसी अन्य उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रवेश नहीं किया बल्कि इसके पीछे यथार्थवाद की भावना थी जिसका आधार उसकी अपनी परिस्थितियों की वास्तविकता तथा उसके आसपास के राजनीतिक जीवन के तथ्य थे जिनके कारण उसने गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई।”

स्वाधीन भारत की नीति सैनिक अथवा राजनीतिक गठबन्धनों से तटस्थ रहने की थी, पर यह निष्क्रियता की नीति नहीं थी। यह नीति परिस्थितियों के अनुकूल विश्वशान्ति और उपनिवेशों की स्वाधीनता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में क्रियाशीलता की थी। गुट-निरपेक्ष देश के रूप में भारत की भूमिका को शीघ्र ही मान्यता मिल गई। भारत ने जितने सफल रूप से इस नीति को आगे बढ़ाया, यह कल्पित उदाहरणों से स्पष्ट है जिन्हें टी. एन. कौल ने निम्नवत् प्रस्तुत किया है—

1. सबसे पहले कोरिया के संकट के समय भारत के स्वतन्त्र फैसला कर सकने की क्षमता को तथा शीतयुद्ध से प्रभावित इस मामले में उसकी कार्यवाही की मान्यता प्राप्त हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत तटस्थ राष्ट्रों के प्रत्यावर्तन-आयोग का अध्यक्ष था। उसने युद्धबन्धियों की बदला-बदली के कार्य के निरीक्षण के लिए अपनी सेना भी भेजी। यह उसकी स्वतन्त्र विदेश नीति, गुट-निरपेक्षता और कोरिया के संकट के प्रति उसके सैद्धान्तिक दृष्टिकोण की मान्यता थी।

2. 8 मिनम्बर, 1951 को भारत ने सानफ्रांसिस्को में होने वाली जापान शान्ति-सन्धि में अमेरिका की शर्तों पर आपत्ति कर, एक बार फिर अपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण का परिचय दिया। भारत ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, इसके साथ ही उसने जापान के साथ युद्ध-समाप्ति के लिए कार्यवाही की।

3. कोरिया की तरह ही हिन्दचीन में भी भारत का प्रयास इस क्षेत्र को शीतयुद्ध का शिकार बनाने से रोकना था। भारत की दृष्टि में यह सफ़ट साम्राज्यवाद की पुनः स्थापना के विरुद्ध राष्ट्रवादी संघर्ष था। यहाँ भी भारत ने अमेरिका के इस इरादे का विरोध किया कि वह फ्रांसीसी सरकार द्वारा वियतमिन्ह के विरुद्ध युद्ध में तेज़ी लाने का समर्थन करे। हिन्दचीन पर होने वाले जिनेवा सम्मेलन में भारत ने भाग नहीं लिया, लेकिन परदे के पीछे उसकी सक्रियता ने वार्ता में सहायता की। भारत ने साम्यवादी देशों की आशंका कम करने के लिए जो भूमिका भरा की थी उसे ब्रिटिश सरकार ने भी मान्यता दी। जब जिनेवा-सम्मेलन एक अन्तर्राष्ट्रीय निरन्तरण आयोग की स्थापना के लिए महमत हो गया तो भारत को उनका अध्यक्ष चुना गया।

4. 1956 के स्वेज नहर के सफ़ट के प्रति भारत के रवैये ने गुट-निरपेक्ष देशों की एकजुटता को मजबूत करने और उनकी स्वाधीनता के प्रदर्शन में सहायता की। भारत ने ब्रिटेन-फ्रांस की कार्यवाही का तीव्र विरोध किया क्योंकि वे मैनिफ़ेस्ट शक्ति की राजनीति से समस्या का समाधान करना चाहते थे जो 19वीं शताब्दी में प्रचलित थी। भारत का प्रयास सत्रपेंशन पक्षों के बीच शत्रुता कम करने का था। अन्तिमपूर्ण वार्ता और समझौते के लिए ब्रिटेन, फ्रांस व मिस्र के विदेश-मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत योजना में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को शामिल किया गया। भारत ने इजरायल और मिस्र के बीच गाजापट्टी में सस्पायी युद्ध-विराम के अधीक्षण के लिए तैनात समुक्त राष्ट्रसेना के लिए टुकड़ी भी भेजी।

5. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था शीतयुद्ध हो या गरम युद्ध, इसका विकल्प अन्तिमपूर्ण सह-अस्तित्व ही है। इसी परिभाषा उन्होंने इस तरह की कि यह एक मानसिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो मतभेदों और विरोधों में सामंजस्य स्थापित करता है; विभिन्न धर्मों, सिद्धान्तों, आर्थिक सामाजिक पद्धतियों को समझने और उनमें समानताएँ ढूँढ़ने की चेष्टा करता है और संघर्ष अथवा सैनिक समाधानों की शब्दावली में सोचने से इंकार करता है। इसी दृष्टिकोण को सहितावद्ध कर पाँच सिद्धान्तों अथवा पंचशील का नाम दिया गया। अप्रैल, 1955 में वाँडुम में होने वाले पहले अफ़्रीकावादी सम्मेलन में स्वीकृत 'विश्वशान्ति एवं सहयोग की घोषणा' में भी इन्हें शामिल किया गया। वाँडुम सम्मेलन के बाद के वर्षों में न केवल एशिया और अफ़्रीका के देशों में गुट-निरपेक्षता का समर्थन बराबर बढ़ता रहा, बल्कि शीतयुद्ध के दोनों पक्षों की ओर से भी इस धारणा को मान्यता तथा सम्मान प्राप्त हुआ।

6. गुट-निरपेक्षता की धारणा के विकासक्रम में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी सितम्बर, 1961 में बेलग्रेड में होने वाला गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में भारत की भूमिका का मुख्य उद्देश्य चर्चा के रूप में शीतयुद्ध का मरुट दूर करने की ओर मोड़ना था। अक्टूबर, 1964 में काहिरा में होने वाले गुट-

निरपेक्ष राष्ट्रों के दूसरे सम्मेलन में भी भारत ने इसी आधारभूत दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया ।

सभी सम्मेलनों में भारत का प्रयास गुट-निरपेक्ष देशों को अन्तर्मुखी समूह बनाने से रोकने और अधिक से अधिक देशों को गुट-निरपेक्ष बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था । इन सम्मेलनों में भाग लेने वालों के लिए एक मानदण्ड नियत किया गया जिसे काहिरा तथा वेलप्रेड सम्मेलनों में स्वीकार कर लिया गया । गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलनों में भाग लेने वालों की बढ़ती हुई संख्या इस बात का प्रमाण थी कि गुट-निरपेक्ष और गुटबन्दी वाले, जैसे देशों में स्थिति बदल रही है । इसके साथ ही सम्मेलन की कार्यवाही से यह भी परिलक्षित होता था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बरीयताएँ बदल रही हैं ।

कुछ और भी उदाहरण भारत की गुट-निरपेक्ष नीति की सार्थकता को सिद्ध करते हैं—

7. नवम्बर, 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत को पश्चिमी देशों से बिना शर्त अविलम्ब सैनिक सहायता प्राप्त हुई और रुम का समर्थन भी मिला ।

8. सितम्बर, 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में असहमता की नीति की शक्ति को एक बार फिर सिद्ध कर दिखाया गया । पाकिस्तान, सीटो और सीटो जैसे शक्तिशाली सैनिक गुटों का सदस्य होने पर भी किसी से कोई प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त नहीं कर सका । टर्की और ईरान ने उसे सैनिक सहायता देने का आश्वासन तो दिया किन्तु अन्य राज्यों के विरोध के कारण जिसमें पश्चिमी राज्य भी सम्मिलित थे, पाकिस्तान की मदद पर आ नहीं सके । इस युद्ध में पाक-दृष्टिकोण से यह गिद्ध हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुटों में सम्मिलित होने की नीति सार्थक नहीं है ।

9. जनवरी, 1966 में श्री शास्त्री के निधन के बाद श्रीमती गांधी ने अपने कार्यकाल में गुट-निरपेक्ष की विदेश-नीति के आधारभूत सिद्धान्तों में किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन न करते हुए उसे राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में अधिक प्रभावी बनाया और उसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पूर्वापेक्षा अधिक व्यावहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया । विभिन्न दवावों के बावजूद इन्दिरा सरकार हिमी भी महाशक्ति या गुट-विशेष के प्रभाव में नहीं आई । प्रारम्भ से ही अमेरिका ने श्रीमती गांधी के प्रति दबाव की नीति पर अमल किया, लेकिन वह उन्हें अपनी धमकियों से झुका नहीं सका । वगलादेश के सन्दर्भ में श्रीमती गांधी ने अमेरिकी प्रशासन के रवैये का तीव्र विरोध किया तो दूसरी ओर रुम के मैत्रीपूर्ण रूप का स्वागत किया । रुम के साथ अगस्त, 1971 में मैत्री-सन्धि की गई लेकिन गुट-निरपेक्षता और स्वयं की निर्णय-शक्ति पर उनमें कभी झग नहीं आई । सन्धि की धारा 4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि मोक्षियन गण भारत

की गुट-निरपेक्ष नीति को स्वीकार करता है और उसे विश्व-शान्ति के लिए उपयोगी मानता है। इस अनुच्छेद के शब्द अविकल रूप में इस प्रकार हैं—

“भारत सशक्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र सभ की शान्ति-प्रिय नीति का सम्मान करता है जिसका उद्देश्य सभी राष्ट्रीयों के साथ मित्रता और सहयोग को सुदृढ़ करना है।”

“सोवियत समाजवादी जनतन्त्र सभ भारत की गुटमुक्त नीति का सम्मान करता है और इसमें पुनः आस्था प्रकट करता है कि विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोयम रखने तथा सशर में तनाव कम करने में इस नीति का महत्वपूर्ण स्थान है।”

अनुच्छेद 8 के ये शब्द गुट-निरपेक्ष नीति को बल प्रदान करने और सैनिक गठबन्धन से दूर रहने की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं—

“दोनों देशों के बीच विद्यमान परम्परागत मित्रता के अनुसार महान् दोनों सविद पक्ष निष्ठापूर्वक घोषित करते हैं कि वे किसी भी ऐसे सैनिक गठबन्धन में, जो किसी एक पक्ष के विरुद्ध हो, न तो सम्मिलित होंगे और न भाग लेंगे।”

“प्रत्येक महान् सविद-पक्ष यथनवद्ध है कि वह एक-दूसरे पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा तथा अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं होने देगा जिससे दूसरे पक्ष की सैनिक क्षति होने की आशंका हो।”

सन्धि के सभी अनुच्छेदों की शब्दावली शान्तिपूर्ण सह-प्रतिस्तर की विचारधारा को गुप्त करने वाली, सैनिक गठबन्धनों का तिरस्कार करने वाली, विवादों को ‘पारस्परिक सम्मान और सूझबूझ द्वारा द्वि-पक्षीय ढंग से’ निपटाने वाली है। सन्धि सम्पन्न होने के उपरान्त अभी तक दोनों पक्षों की ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो गुट-निरपेक्षता के विरुद्ध जाती हो या किसी भी रूप में सैनिक गठबन्धन को समर्थन देती हो। दिसम्बर, 1971 में बंगलादेश के कारण जो भारत-पाक युद्ध हुआ उसने गुट-निरपेक्षता की नीति को पुनः सही सिद्ध कर दिखाया। पाकिस्तान को हथियार देने वाले देश पाकिस्तान को अगूठा दिखा गए और देखते ही देखते पाकिस्तान अपने एक भू-खण्ड को अपनी ही भूलतता से खो बैठा।

10. मार्च, 1977 के ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तन के बाद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में यह भाषका प्रकट की जाने लगी थी कि नई जनता सरकार भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति पर खल मकेगी या नहीं, अथवा उसका झुकाव अमेरिका और उनके साथी राष्ट्रों की ओर हो जाएगा, लेकिन जनता सरकार ने सभी आशंकाओं को निर्मूलत करते हुए भारत की स्वतन्त्र विदेश-नीति को अनिशीलता और व्यावहारिकता प्रदान की। जनता पार्टी ने जिस स्पष्ट और अमदिग्ध ढंग से गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाया, उसमें भारत की विदेश-नीति को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। सत्ता में आने ही जनता पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर यह देखा कि भारत के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध उसने

बढ़िया नहीं हैं जितने होने चाहिए। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के तथाकथित साम्यवादी गुट के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध मधुर थे, लेकिन आपात-स्थिति के कारण पश्चिम के उदारवादी लोकतन्त्री देशों के सामने उसकी तस्वीर धुँधला गई थी। जनता सरकार ने विश्व के विभिन्न देशों के साथ—विशेषतः अत्यधिक मवेदनशील क्षेत्रों में पड़ोसी देशों से अपने विगड़े सम्बन्धों को सुधारने के प्रयास आरम्भ कर दिए। सर्वश्री देसाई और चरणसिंह की प्रमत्त, नेपाल और श्रीलंका की और श्री बाजपेयी की अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल व पाकिस्तान की यात्राएँ उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी बंगलादेश के प्रेसीडेंट जियाउर रहमान की भारत यात्रा और पाकिस्तान के जनरल जिया-उल-हक की प्रस्तावित भारत-यात्रा। जनता सरकार ने पड़ोसी देशों की गलत पहिमियों को दूर करने और उनमें विश्वास जगाने में पहल ही। उदाहरणार्थ बंगलादेश को गंगा नदी सम्बन्धी विवाद में कुछेक अल्पकालीन गियायतें देकर तथा नेपाल को व्यापार और पारगमन समस्या पर कुछ छूटें देकर उनसे प्रति सद्भावना प्रकट की गई। दक्षिण एशिया का बड़ा और ताकतवर देश होने के कारण भारत का ही यह दायित्व था कि वह इन देशों के वास्तविक या काल्पनिक भयों का निवारण करे और अपने नेक इरादों के प्रति इन देशों में विश्वास की भावना पैदा करे। भारत तथा छोटे पड़ोसी देशों के बीच तनावरहित सम्बन्धों की शुरुआत होने से भारत की नेकनीयती के सम्बन्ध में सन्देह की भावना समाप्त हो गई। जनता पार्टी की सरकार ने द्विपक्षीय सम्बन्धों का विकास किया और ऐसी भ्रामक धारणाओं को दूर किया कि भारत किसी एक या दूसरी महाशक्ति से प्रतिबद्ध होना जा रहा है।

11. जनवरी 1980 में श्रीमती गान्धी पुनः सत्तारूढ़ हो गई। उनके इस द्वितीय कार्यकाल में अभी मार्च, 1982 के मध्य तक भारत की गुट-निरपेक्ष तन्त्रीय और अधिक शक्ति के साथ उभरी है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के हर क्षेत्र में श्रीमती गान्धी ने भारत की निर्भीक स्वतन्त्र नीति को उजागर किया है। भारत सभी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध के विकास के लिए मत्न प्रयत्नशील है। वह किसी भी बड़े राष्ट्र या महाशक्ति के दबाव से प्रेरित होकर कोई नीति नहीं अपनाता। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भारत की भूमिका रचनात्मक रही। भारत ने हिन्द-महासागर में बड़ी शक्तियों की नैतिक उपस्थिति का बराबर विरोध किया। भारत सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील रही है कि एक स्वतन्त्र प्रभुमत्ता सम्पन्न और गुट-निरपेक्ष राज्य के लिए अफगानिस्तान का परम्परागत दर्जा बना रहे। भारत में सरकार बदल जाने से पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति के बारे में कुछ घटकनै लपाई जाने लगी थी। इसे देखते हुए नई सरकार ने सबसे पहले जो काम किए उनमें एक काम यह भी था कि उसने अपनी नीति का सारसत्य बताया जो यह था कि भारत इस क्षेत्र में शान्ति की स्थापना की स्थिति मजबूत करना चाहता है, ताकि इन देशों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहकर अपने लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में प्रयत्न करने का मौका मिले। उच्चस्तरीय दूतों के

माध्यम से भारत में पारस्परिक विश्वास और मैत्री-सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की और प्रमुखतात्मक समानता तथा एक-दूसरे राज्य के आन्तरिक मामलों में अस्वतंत्रता के सिद्धान्तों के आधार पर अपने सभी पड़ोसियों के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को संवर्धित करने की कोशिश की है ताकि इस क्षेत्र में सार्वक सहयोग को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस तरह राज्यों की प्रमुखतात्मक समानता पर आधारित पारस्परिकता अन्तर्गत प्रतियोगिता के सम्बन्धों का आधार बन सकेगी। भारत के दृष्टिकोण की इस ईमानदारी को सराहा गया है। 13 मार्च, 1982 को श्रीमती गांधी ने बाहरी दबाव के प्रति चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत स्वतन्त्र गुट-निरपेक्ष नीति पर चलता रहेगा और किसी के आगे नहीं झुकेगा। श्रीमती गांधी ने कहा, "कुछ कारणों से बहुत से देश गुरु से ही भारत के खिलाफ रहे हैं। उनके लिए अगर हम सही भी कहते हैं तो वह भी गलत है। अब हम इन सब बातों के अन्त्य हो गए हैं। हमें अब ये बातें तनिक भी विचलित नहीं करतीं। यह निर्णय हमें करना है कि हम वहाँ जाना चाहते हैं और उस घेरे तक पहुँचने के लिए क्या कदम उठाए जाएँ।"¹

एक गुट निरपेक्ष देश के रूप में भारत की छवि और प्रतिष्ठा में निरन्तर निम्नार आ रहा है।

गुट-निरपेक्षता के बदलते हुए रूप (Changing Patterns of Non-alignment)

गुट-निरपेक्षता की नीति समय के साथ अधिकाधिक सक्रिय और व्यावहारिक बनती जा रही है। प्रारम्भ में इस नीति में आदर्शवाद का आवश्यकता से अधिक गुट था, लेकिन गुट-निरपेक्ष देश अब यह अधिक अच्छी तरह समझने लगे हैं कि कोई भी नीति सार्वक तभी हो सकती है जब उसे बंधनवाद के घरातल पर उतारा जाए। आज इस तथ्य की समझ लिया गया है कि गुट-निरपेक्षता की नीति की सफलता और प्रभावशीलता के लिए अनिवार्य है कि इसके आधार पर राष्ट्रीय हितों का संरक्षण सम्भव बनाया जाए। भारत गुट-निरपेक्ष देशों का अगुसा रहा है। वस्तुतः, इस नीति का प्रवर्तक होने का श्रेय ही भारत को है। स्व नेहरू के समय तक गुट-निरपेक्षता की नीति में आदर्शवाद दृढ़ता अधिक छाया रहा कि अधिवांश राजनीतिक क्षेत्रों में यह सन्देह व्याप्त हो गया कि क्या गुट-निरपेक्ष नीति पर चलकर भारत अपने राष्ट्रीय हितों का पोषण और संचालन कर सकता है। स्व शास्त्री के समय गुट-निरपेक्षता की नीति कुछ अधिक सक्रिय और व्याववादी बनी और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में तो यह नीति बहुत अधिक व्याववादी बन गई। श्रीमती गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी राष्ट्र के साथ मैत्रिक सन्धि में बंधे बिना भी एक राष्ट्र वृष्टनीतिक उपायों तथा मैत्र-मैत्रिक मैत्री-सन्धियों के बल पर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। श्रीमती गांधी पूरी तरह गुट-निरपेक्ष रहते हुए इस जैसी

महाशक्ति की प्रगाढ़ मैत्री अजित करने में सफल हुई और 1971 की यह भारत-रूस-मैत्री सन्धि गुट-निरपेक्ष नीति के नए दृष्टिकोण की परिचायक है। इस सन्धि द्वारा सैनिक गुटबन्दी में शामिल हुए बिना ही भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की गई है।

हाल ही के वर्षों में गुट-निरपेक्षता की नीति में पारस्परिक आर्थिक सहयोग के तत्त्व पर विशेष बल दिया जाने लगा है। काहिरा में हुए द्वितीय शिखर-सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष देशों के पारस्परिक आर्थिक विकास और सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया और तब से यह तत्त्व अधिक विकसित हुआ है। बिस्वात कूटनीतिज्ञ और समुक्तराज्य अमेरिका में भारत के भूतपूर्व राजदूत टी एन कौल ने ठीक ही लिखा है कि—“अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राजनीतिक पहलू की अपेक्षा आर्थिक पहलू पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिए जाने से गुट-निरपेक्षता की धारणा की सार्थकता गिढ़ हुई है।”

गुट-निरपेक्षता का परस्पर विरोधी स्वरूप भी अस्तित्व में है जिसका स्पष्ट उदाहरण पश्चिमी एशिया में देखने को मिलता है। समुक्त अरब-गणराज्य, सीरिया आदि अरब-राष्ट्र इजरायल के साथ सैनिक संघर्ष से विवश होकर सोवियत संघ के साथ इस तरह बंध गए हैं कि उनकी गुट-निरपेक्षता सन्देहास्पद बन गई है। फिर भी अरब-राष्ट्र इस बात के प्रति सचेष्ट हैं कि उनकी राजनीतिक सम्प्रभुता पर धाँच न आए। दूसरे शब्दों में पश्चिमी-एशिया का यह क्षेत्र एक तरह से 'सचेत और सरवधान गुटबन्दी' का क्षेत्र बन गया है।

वर्तमान परिस्थितियों में गुट-निरपेक्षता का महत्त्व

आज के युग में गुट-निरपेक्षता का महत्त्व मुख्यतः इन कारणों से स्पष्ट है—

1. गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने वाले राष्ट्रों की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

2. समुक्त राष्ट्रसंघ में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की आवाज आज अधिक सबल है।

3. गुट-निरपेक्ष जगत् को विश्व की महाशक्तियों के बीच सन्तुलनकारी शक्ति के रूप में मान्यता मिल चुकी है। पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों ही पक्ष गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का समर्थन पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनमें इन देशों को आर्थिक और प्रादेशिक सहायता देने की होड़-सी लगी हुई है। दोनों ही महाशक्तियाँ कूटनीतिक समर्थन देकर अधिकाधिक गुट-निरपेक्ष देशों को अपने पक्ष में करने को उत्सुक हैं।

4. आज के आणविक युग की माँग है सह-अस्तित्व। गुट-निरपेक्षता की नीति इस सह-अस्तित्व की धारणा को बल प्रदान करती है। यह 'जींओ जीरे जीने दो' के सिद्धान्त में विश्वास करती है।

5. गुट-निरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण को हतोन्माहित करती है। इसका विशेष बल आर्थिक समृद्धि और शान्तिपूर्ण विकास पर है तथा यह गंभीर सैनिक उपस्थितियों को महत्त्व देती है।

6. गुट-निरपेक्ष हर प्रकार के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरोधी है तथा रचनात्मक राष्ट्रवाद और राष्ट्रों के स्वतन्त्र अस्तित्व की पोषक है।

7. गुट-निरपेक्षता संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के गिद्दान्तों को बल प्रदान करती है तथा विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के उपायों का समर्थन करती है।

8. गुट-निरपेक्षता रण-भेद और जातिवाद में विश्वास नहीं करती। इसका नारा है 'विश्व-वन्धुत्व'।

9. यह नीति सैनिक गुटों और सैनिक सन्धियों का निरस्तार करते हुए राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने वाली है। इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है।

10. गुट-निरपेक्षता की नीति लचीली है तथा समय के अनुरूप ढलने की क्षमता रखती है। इस प्रकार यह सतत् विकसनीय है। यह निर्भीकता और नाहन की नीति है जो न्याय की रक्षा के लिए तलवार उठाने की प्रेरणा भी देती है।

आज मानव-जाति आणविक शस्त्रास्त्रों के बास्सी डेर पर बँधी हुई है और जरासी भी चिनगारी इस डेर का विस्फोट कर महाविनाश कर सकती है। इस खतरे से बचने का एक ही मार्ग है कि सहअस्तित्व और गुट-निरपेक्षता की नीति पर चला जाए। राजनीतिक समीक्षकार आनन्द जैन ने अपने एक लेख में लिखा था—

'सन् 1961 में गुट-निरपेक्षता के तीन आधार-स्तम्भों—नेहरू, नासिर और टोटी ने गुट-निरपेक्षता के पाँच आधार स्वीकार किए थे। पहला, सदस्य-देश स्वतन्त्र नीति पर चलता हो, दूसरा, सदस्य-देश उपनिवेशवाद का विरोध करना हो; तीसरा, सदस्य-देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो; चौथा, सदस्य-देश ने किसी बड़ी ताकत में द्विपक्षीय सैनिक समझौता न किया हो; और पाँचवाँ, सदस्य-देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो। ये पाँच मोटे सिद्धान्त आज भी गुट-निरपेक्षता की ठोस कमीठी हैं, हालाँकि इस बात पर भी जोर देना जरूरी है कि गुट-निरपेक्ष देशों को विश्व-शान्ति, सह-अस्तित्व तथा राष्ट्र-मंड में पूरी आस्था हो।'

आरम्भ में रूस और अमेरिका दोनों ही गुट-निरपेक्षता को अनुत्पापूर्ण दृष्टि में देखते थे। रूसी नेतृत्व सम्भक्ता था कि गुट-निरपेक्ष देश अमेरिका के पीछे हैं और दूसरी ओर अमेरिकी नेतृत्व गुट-निरपेक्ष देशों को रूस का पिछलग्नु मानता था। अमेरिकी केन्द्रवादी विदेश मंत्री डेलस ने जो गुट-निरपेक्षता की नीति को 'अनैतिक' तक कह डाला था, लेकिन यथार्थता को सम्भक्ते हुए थी कैंनेडी और थी रूजवेल्ट ने इस नीति को सम्मान देना आरम्भ किया और आज यह बात अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्वेनाओं से छिरी नहीं है कि दोनों ही महाशक्तियाँ गुट-निरपेक्षता की अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय का एक महत्वपूर्ण भाग मानती हैं और गुट-निरपेक्ष देशों से अधिकाधिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। पश्चिमी यूरोप और चीन के रूप में जो नए शक्ति-केन्द्र विकसित हुए हैं उनकी विदेश-नीति का भी यह एक मुख्य लक्ष्य है कि गुट-निरपेक्ष देशों के साथ अधिकाधिक मैत्री सम्बन्ध कायम किए जाएँ।

गुट-निरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक महत्त्व को कम करके आँकना वस्तु-स्थिति की उपेक्षा करना होगा। समुक्त राष्ट्रसंघ के आधे से अधिक देश गुट-निरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं और विश्व-संस्था के विभिन्न मंचों पर गुट-निरपेक्ष देशों ने "विश्वशान्ति, उपनिवेशवाद के अन्त, परमाणु-प्रस्त्रों पर रोक, अन्तरिक्ष का उपयोग युद्ध के लिए करने पर रोक, निःशस्त्रीकरण, हिन्दमहासागर की शान्ति-क्षेत्र घोषित करना आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्यवाही की है और सफलता पाई है।" समीक्षाकार आनन्द जैन ने ठीक ही लिखा है—“गुट-निरपेक्ष देशों के संगठित प्रयत्न का ही परिणाम है कि आज विश्व के अधिकांश देश आजाद हो गए हैं और जो देश गुलाम रह गए हैं, उनके लिए भी राष्ट्रसंघ की मार्फत ये देश दबाव डाल रहे हैं। अगर गुट-निरपेक्ष देश मिलकर आवाज न लगाते तो दक्षिण-अफ्रीका की जाति-भेद नीति, रोडेशिया की गैर-कानूनी सरकार की मनमानी, अंगोला और मोजाम्बिक पर पुर्तगाली शासन आदि पर राष्ट्रसंघ बार-बार कार्यवाही न करता और बड़े राष्ट्रों की छत्रछाया में उपनिवेशवाद चलता रहता।”

गुट-निरपेक्षता आधुनिक सन्दर्भ में साम्राज्यवाद-विरोध की सूचक है। इतिहास के इस तथ्य को मुलाया नहीं जा सकता कि आज अधिकांश गुट-निरपेक्ष देश वे ही हैं जो कुछ समय पूर्व तक औपनिवेशिक दाम्पत्य के शिकार थे। यदि पिछली साम्राज्यवादी शक्तियाँ, जो आज भी छद्मवेश में साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाएँ सजोए हुए हैं, मन ही मन गुट-निरपेक्षता से ईर्ष्या करती हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नवोदित सम्प्रभु राज्य अपने पिछले 'स्वामियों' का प्रभुत्व या प्रभाव स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। राजनीतिक प्रभुत्व की बात तो दूर रही, एशिया और अफ्रीका के स्वतन्त्र राष्ट्र तथाकथित 'बड़े राष्ट्रों' के आर्थिक प्रभुत्व के प्रति भी सचेत हैं, कठिनाइयाँ सहकर भी 'आर्थिक साम्राज्यवाद' का विरोध कर रहे हैं। बिगन कुछ वर्षों का इतिहास साक्षी है कि विश्व के अनेक भागों में 'डॉलर साम्राज्यवाद' की कितनी निराशा हाथ लगी है। डॉलरों के जिम 'स्वामी' को कभी राष्ट्रीय आन्दोलनों और स्वतन्त्रता के पुजारियों का संरक्षक समझा जाता था उसे आज हर जगह मन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। गुट-निरपेक्ष नीति कितनी प्रभावी सिद्ध हो सकती है, इसका एक सबल प्रमाण यही है कि पहले तो भारत को विश्व के दोनों गुटों से महायत्ना मिलती रही, लेकिन जब डॉलरशक्तियों ने अपनी दबाव-नीति अपनाई तो भारत भीषण मकड़ों को भी भेज गया क्योंकि दूसरे शक्तिशाली गुट ने भारत की गुट-निरपेक्षता को पूर्ण सम्मान दिया और इस तरह एक महान् पूँजीवादी शक्ति के अनेक 'पड़पन्धों' को विफल कर दिया गया। यह सब कुछ 'बिना किसी शर्त' के हुआ। भारत की गुट-निरपेक्षता पर तानिक भी धाँस नहीं आई। निरन्तर-प्रशासन ने अपने जीवन की मध्या में अन्तर्गतत्वा यह समझ लिया था कि भारत की गुट-निरपेक्षता को गण्डित करने का उसका प्रयास स्वयं उसके लिए 'एक बदनामी' और 'एक ज्ञानिचार्य' कायों सिद्ध हुआ है और इसलिए 'महापुरुष' रीतिगर्भ भारतीय भागजनों को दूर करने की 'वृत्तीय नवावाजिरी' दिखाने लगे। यदि हम भाग्य

और पाकिस्तान को तराजू के दोनों पलड़ों में रखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि गुट-निरपेक्षता अधिक प्रभावी और कामयाब सिद्ध हुई है या सैनिक गुटबन्दी की नीति।”

5 सितम्बर 1981 के हिन्दुस्तान का सम्पादकीय मूल्यांकन है कि—

“निर्गुट आन्दोलन को प्रारम्भ हुए बीस वर्ष पूरे हो चुके हैं। आन्दोलन का पहला सम्मेलन सितम्बर 1961 में वेल्श में हुआ था जिसमें उसके संस्थापक मार्शल टीटो, प नेहरू और श्री नासिर के अनिश्चित धाना के राष्ट्रपति एन्सुमा, साइप्रस के राष्ट्रपति मकारियोस तथा इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति डॉ सुकर्णो जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों ने भाग लिया था। पहले सम्मेलन में कुल पच्चीस देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उसकी बीसवीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्रमण्डल में आयोजित एक बैठक में 96 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघ की कुल सदस्य सभा के दो-निहाई देश निर्गुट आन्दोलन से सम्बद्ध हो चुके हैं। इनमें प्रायः सभी राजनीतिक प्रणालियों में विश्वास करने वाले और विभिन्न शासन-व्यवस्थाओं वाले देश हैं। आन्दोलन की सफलता और निरन्तर विकास का यह एक स्पष्ट प्रमाण है।

निर्गुट आन्दोलन की आवश्यकता उस समय महसूस की गई जब संयुक्त राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्ट्र दो गुटों में बँट चुके थे और उनकी आपसी टकराव के कारण जो सदस्य इन दोनों गुटों से अलग थे, वे कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। निर्गुट आन्दोलन ने प्रारम्भ से ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद जिसमें यहूदीवाद भी शामिल है, विदेशी घेरावट और ‘महाशक्ति तथा गुटों की राजनीति’ के विरुद्ध रुख अपनाया, लेकिन पक्षि ऊपर से देखने में ये बातें ऐसी हैं जिनसे किसी का विरोध नहीं हो सकता तथापि आन्दोलन को अपने रास्ते में कम कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है। इसका एक कारण सदस्य-राष्ट्रों की भिन्नता भी रही है। प्रायः उनके हित आपस में टकराए हैं। ईराक-ईरान युद्ध एक उदाहरण है। दोनों ही देश निर्गुट आन्दोलन के सदस्य हैं, फिर भी विगत एक वर्ष से उनके बीच युद्ध जारी है। निर्गुट आन्दोलन की ओर से विदेश-मन्त्रियों की एक समिति उनका विवाद हल कराने का प्रयास कर रही है किन्तु कई महीनों के प्रयत्नों के बावजूद उसे अब तक कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। इसी प्रकार अगोला की समस्या है। अरब देशों पर इजरायली हमले की समस्या है। हमलावरों के विरुद्ध निर्गुट राष्ट्र केवल विरोध प्रकट करके रह जाते हैं, अभी तक वे इस स्थिति में नहीं हैं कि उनका सक्रिय प्रतिकार कर सकें।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि विश्व राजनीति पर निर्गुट आन्दोलन का रचनात्मक प्रभाव पड़ा है और जिस प्रकार से शान्ति को नित्य नए-नए खतरे पैदा हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए आन्दोलन को अधिक सशक्त बनाने के प्रयास और कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है। चीनयुद्ध के आसार फिर बनने लगे हैं, हथियारों की होड़ पुनः शुरु हो गई है, छोटे-मोटे देशों के लिए फिर नए खतरे पैदा हो रहे हैं। निर्गुट राष्ट्रों को मिलकर इन सब समस्याओं पर सोचना चाहिए और उनके हल खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आन्दोलन के

जनक मार्शल टीटो और पं नेहरू को केवल स्मरण करके नहीं छोड़ देना चाहिए वरन् उन क्षितिजों को भी निरन्तर ध्यान में रखना चाहिए जो आन्दोलन की स्थापना के समय उनकी कल्पना में थे ।”

पिछले वर्षों में चीन और पाकिस्तान ने भारत की गुट-निरपेक्षता को ‘दुहरे गठबन्धन’ (Double Alliance) की सजा दी । उनका तर्क यह है कि भारत गुट-निरपेक्षता के नाम पर अमेरिका और रूस दोनों से सहायता प्राप्त करता रहा है और अब केवल रूस से सहायता प्राप्त करता है, इस प्रकार या तो भारत की गुट-निरपेक्षता ‘दुहरा-गठबन्धन’ का ही छद्मनाम था या अब भारत ने रूस के साथ बन्धकर गुट-निरपेक्षता को तिलांजलि दे दी है, लेकिन ये दोनों ही आलोचनाएँ गलत हैं और इस बारे में भारत का गुट-निरपेक्षता सम्बन्धी पूर्व-विवेचन स्थिति को भली प्रकार स्पष्ट कर देता है । आज गुट-निरपेक्षता एक सवल तत्त्व है और प्रबल नीति है जिसे दुनिया की कोई शक्ति नकार नहीं सकती और यदि नकारती है तो अपने आपको घोला देती है ।



द्वि-ध्रुवीयता (द्वि-केन्द्रीयता) एवं बहु-केन्द्रवाद (BIPOLARITY AND POLYCENTRISM)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में द्वि-ध्रुवीयता अथवा द्वि-केन्द्रीयता का सरलतम अर्थ है विश्व का दो शक्ति-मुटो या केन्द्रों में विभाजित हो जाना। इसी प्रकार बहु-केन्द्रवाद का आशय है विश्व में शक्ति के केवलमात्र दो केन्द्रों की अपेक्षा अनेक शक्ति केन्द्रों का उदय हो जाना। द्वितीय महायुद्ध के तुरन्त बाद विश्व द्वि-ध्रुवीयता (Bipolarity) की ओर बढ़ा और सन् 1960 के आते-आते इस द्वि-ध्रुवीयता के बन्धन शिथिल पड़ने लगे और विश्व शून्य शून्य: बहु-केन्द्रवाद (Polycentrism) की ओर अग्रसर होने लगा। आज स्थिति यह है कि विश्व में शक्ति के दो से अधिक केन्द्र स्पष्टतः प्रकट हो चुके हैं, यद्यपि उनका स्वरूप सुनिश्चित नहीं हुआ है और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ विचारकों में मनभेद भी है कि क्या वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-व्यवस्था को 'बहुध्रुवीय' (Multi-polar) कहा जा सकता है। अग्रिम पक्तियों में हम द्वि-ध्रुवीयता से बहु-केन्द्रवाद की ओर बदलते इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे।

कठोर द्वि-ध्रुवीयता (Tight Bipolarity)

द्वितीय महायुद्ध का एक अत्यन्त क्रान्तिकारी और सुदूरगामी परिणाम यह निकला कि प्राचीन शक्ति-सन्तुलन का पूरी तरह विनाश हो गया। युद्ध के उपरान्त दो प्रमुख फासिस्ट शक्तियों—जर्मनी और इटली का पूर्ण पराभव हो गया। ब्रिटेन राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बहुत क्षीण हो गया। यूरोपीय महाद्वीप पर यदि कोई देश युद्धकालीन महान् शक्तियों के बावजूद भी शक्तिशाली होकर निकला तो वह था सोवियत संघ। उसकी विशाल प्रदेशों की उपलब्धि हुई और उसकी आर्थिक नीतियों का अनेक पड़ोसी देशों पर प्रभाव पड़ा। युद्धकाल में तो उसने अपनी सीमाओं का पश्चिम में विस्तार कर ही लिया, बाद में उसके सीमान्तों में वे सम्पूर्ण प्रदेश भी शामिल हो गए जो किसी समय जारकालीन रूस के भाग थे। उसका विश्व की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा और साम्यवादी सिद्धान्तों तथा जीवन-दर्शन में मानव की आस्था में वृद्धि हो गई। महायुद्ध से विनष्ट और अस्त-व्यस्त संसार में केवल एक ही देश बचा जो सोवियत संघ का मुकाबला करने में सक्षम था और लोकतन्त्रवादी शक्तियों को सशक्त नेतृत्व दे सकता था। यह देश था संयुक्तराज्य अमेरिका, जिसे युद्ध में कोई विशेष क्षति नहीं पहुँची थी, न उसे विनाश-

कारी बमबर्षा का शिकार होना पड़ा था और न उसकी भूमि पर रक्तरजित होली ही खेली गई थी। आर्थिक दृष्टि से वह ससार का समृद्धतम देश था। युद्ध के बाद ससार के सभी पूँजीवादी देश अमेरिकी सहायता के बल पर अपनी अर्थ-व्यवस्था को ठीक रास्ते पर लाने की आशा लगाए बैठे थे।

महायुद्ध के बाद, कुछ काल तक संयुक्तराज्य अमेरिका ही अणु-रहस्य का एकमात्र स्वामी था। सोवियत रूस के लिए यह एक गम्भीर चुनौती थी। स्वभावतः वह शक्ति-सन्तुलन को अपने विपक्ष में जाने से रोकने के लिए अणु शक्ति के रहस्य का पता लगाने में जुट गया और अपने देश की सेनाओं तथा अपने सहयोगी और मित्रराष्ट्रों की सेनाओं का घेरा डाल कर सुरक्षित बचाने का प्रयत्न करने लगा।

महायुद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न हुई उपर्युक्त स्थितियों ने स्पष्ट कर दिया कि विश्व में दो ही प्रमुख शक्ति केन्द्र हैं—सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। युद्धोत्तर विश्व में प्रारम्भ से ही दोनों महाशक्तियाँ परस्पर प्रतिपक्षी बन गईं, घट-दोनों के ही नेतृत्व में दो विरोधी शक्तिशाली गुटों का निर्माण होने लगा। दो गुटों के इस निर्णय की सिद्धान्तों के संघर्ष ने विशेष प्रोत्साहन दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद सिद्धान्तों और आदर्शों पर विशेष आग्रह किया जाने लगा। सोवियत रूस साम्यवाद के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयत्नशील हो गया और संयुक्तराज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्र साम्यवाद को अवरुद्ध करने के लिए कटिबद्ध हो गए। रूस और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियाँ अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गईं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में वे एक दूसरे के प्रति 'असहिष्णु' बन गईं। साम्यवाद की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को अमेरिकी सुदृढ़ विरोध और सन्तुष्टि का मुहावला करना पड़ा।

यद्यपि द्वि-ध्रुवीकरण की प्रक्रिया द्वितीय महायुद्ध के तुरन्त बाद ही शुरू हो गई, तथापि सन् 1947 तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि विश्व द्वि-ध्रुवीय (B polar) बन गया था। इस समय तक रूस का प्रतिरोध मुख्यतः ब्रिटेन के प्रति था, अमेरिका के प्रति नहीं। रूसियों को विश्वास था कि अमेरिका शीघ्र ही पुनः अपनी परम्परागत पृथक्तावादी नीति (Traditional Isolationism) की ओर लौट जाएगा। लेकिन रूसी अनुमान गलत सिद्ध हुआ। महायुद्ध के बाद ब्रिटेन राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक दृष्टि से इतना सक्षम नहीं रहा कि वह पूँजीवादी विश्व को नेतृत्व दे सकता। ब्रिटेन तो शीघ्र ही आर्थिक दृष्टि से अपने पुनः निर्माण के लिए अमेरिका का मुखापेक्षी हो गया। नेतृत्व अमेरिका ने सम्भाल लिया। मार्च, 1947 में ट्रुमैन सिद्धान्त (Truman Doctrine) के अन्तर्गत अमेरिका यूनान और टर्की में ब्रिटिश उत्तरदायित्वों को पूरा करने को सहमत हो गया। अमेरिका ने अपना यह दृढ़ निश्चय व्यक्त कर दिया कि वह उस प्रत्येक देश की सहायता करेगा जो साम्यवाद के विरुद्ध उसकी महायत्ना माँगेगा। अमेरिकी राजनीतिज्ञों को यह विश्वास हो गया कि रूस चीन और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है। अतः अमेरिका को अविलम्ब ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे साम्यवादी प्रसार को प्रभावशाली रूप से 'अवरुद्ध' कर दिया जाए।

अमेरिका और रूस एक दूसरे के प्रति अविश्वास और सन्देह के बशीभूत हो अपने पक्ष में शक्ति-संचय करने लगे। शीतयुद्ध (Cold War) शुरू हो गया जो क्रमशः तेज होता गया। दोनों महाशक्तियों का संघर्ष (Conflict) पहले तो यूरोप तक ही सीमित रहा, किन्तु धीरे-धीरे यह अन्य महाद्वीपों में भी फैल गया। सबसे पहले एशिया संघर्ष-स्थल बना, बाद में मध्यपूर्व और तब लेटिन अमेरिका व अफ्रीका। दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को अपने-अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करने लगीं। सोवियत रूस ने आश्चर्यजनक तीव्रता से पूर्वी यूरोप में अपनी प्रभुता का विस्तार कर लिया। युद्धोपरान्त सन् 1948 तक ही केवल तीन वर्ष की अल्पावधि में ही पूर्वी यूरोप के सात देशों को पूरी तरह 'लाल' बना दिया गया। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद केवल चार वर्ष की अवधि में ही सोवियत रूस ने अणु-बम के रहस्य को खोज लिया। अब स्थिति यह थी कि रूस और अमेरिका दोनों ने केवल एक दूसरे की आणविक हथियारों की धमकी देने लगे वरन् विश्व के हर भाग में और हर मामले में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अमेरिकी गुट और रूसी गुट में समुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर और बाहर अणु-शक्ति के नियन्त्रण व नियमन, निःशस्त्रीकरण, पराजित राष्ट्रों के साथ शान्ति-सन्धियों, जर्मनी व घज़िन के प्रश्नों, यूरोपीय सुरक्षा-समस्याओं, एशिया व अफ्रीका के अल्प-विकसित राष्ट्रों के भविष्य आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी प्रश्नों पर तीव्र वाद-विवाद और कूटनीतिक संघर्ष चालू हो गए।

सोवियत प्रभाव और साम्यवाद के प्रसार को अवरुद्ध करने के लिए अमेरिका की मार्शल योजना के अन्तर्गत यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रभावशाली प्रयत्न किए गए। मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में अक्टूबर, 1947 में रूस ने यूरोप के नौ साम्यवादी देशों के 'कोमिनफार्म' की स्थापना की। रूस ने पूर्वी यूरोप पर अपने नियन्त्रण को और भी कठोर बना दिया। शक्ति के दो धड़े अथवा गुट बन गए और उनमें अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रों के विकास के लिए जी-तोड़ स्पर्धा होने लगी। चीन में साम्यवादियों की महान् विजय ने जहाँ सोवियत गुट को अधिक प्रबल बना दिया, वहाँ अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों में यह भय पैदा हो गया कि उपनिवेश या नवजायत राज्यों में बसने वाली अविकसित जनता चीन का अनुकरण कर पश्चिमी लोकतन्त्र की अपेक्षा कहीं साम्यवादी व्यवस्था को ही पसन्द न करले। अमेरिका व अन्य पश्चिमी राज्यों के राजनेता इस बात से चिन्तित हो गए कि विश्व के अल्प विकसित देश साम्यवादी प्रसार के लिए उत्तम श्रेष्ठ सिद्ध हो सकते हैं। अतः जनवरी, 1949 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमेन ने प्रसिद्ध 'चार सूत्री कार्यक्रम' (Four Point Programme) की घोषणा की।

विश्व का तेजी से दो शक्ति-ध्रुवों या शक्ति-केन्द्रों में विभाजन होता गया। 1 अक्टूबर, 1949 को पेकिंग में बाकायदा साम्यवादियों का जनवादी गणराज्य स्थापित हो गया। पश्चिमी शक्तियाँ साम्यवाद के विरोध के लिए राजनीतिक व

प्राथमिक स्तर के साथ सैनिक स्तर पर भी उतर आई। अमेरिका ने अन्य देशों के साथ सैनिक सन्धियों व पारस्परिक प्रतिरक्षा-सहायता-कार्यक्रम का तरीका प्रारम्भ किया और अप्रैल, 1949 में नाटो की स्थापना हुई। चूंकि नाटो फार्मूला ने यूरोप में अच्छा काम किया, अतः अमेरिका ने इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया। इसके अन्तर्गत नाटो सदस्यों को सैनिक सहायता दी गई, सदस्य देशों में सैनिक बड़े स्थापित किए गए और विभिन्न मैत्री सन्धियाँ क्रियान्वित की गई। सारा संसार इस प्रकार तेजी से दो भागों में बँटता गया—एक था 'साम्यवादी भाग' (The Communist Part) और दूसरा था अमेरिकियों के शब्दों में 'मुक्त विश्व' (The Free World)।

कुछ समय तक यही प्रतीत हुआ कि विश्व का यह द्वि-ध्रुवीकरण या द्वि-केन्द्रीकरण स्थायी बन गया है और भविष्य में यह व्यवस्था अर्थात् द्वि-ध्रुवीयता (B polarity) अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। इस समय जिन तटस्थ राष्ट्रों (Neutrals) का उदय हुआ, उन्हें इस द्वि-ध्रुवीय विश्व (The Bipolar World) में कोई स्थान नहीं दिया गया। रूसी और अमेरिकी दोनों ही भारत जैसे राष्ट्रों को मन्देह की निगाह से देखने लगे। दोनों ही महाशक्तियों ने इस उक्ति पर आचरण किया कि 'जो हमारे साथ नहीं है, वह हमारे विरुद्ध है' (He who is not with us is against us)। युद्धोत्तर विश्व का द्वि-ध्रुवीय चरित्र इस तरह प्रकट हुआ कि अनेक देश वास्तविकता के अन्य पहलुओं को मुला बँडे और इस बात के प्रति आश्वस्त हो गए कि अन्तर्गतगन्वा सम्पूर्ण विश्व दो परस्पर प्रतिरोधी गुटों में बँट जाएगा और द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था पक्की या स्थिर (Fixed) हो जाएगी। स्टीवेन रोजन एव बाल्टर जोन्स के अनुसार इस प्रकार की कठोर द्वि-ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (Tight Bipolar International System) सन् 1945 से 1955 तक अस्तित्व में रही और इस युग में सोवियत अमेरिकी प्रतिस्पर्धा—विशेषकर यूरोप पर, बहुत ही तीव्र रही जिससे न केवल शीतयुद्ध उभर हुआ बल्कि प्रतिद्वन्द्वी सन्धियों और गुटों का निर्माण भी तेजी से हुआ। तत्कालीन रूप में यद्यपि बारसा पकट सन् 1954 तक अस्तित्व में नहीं आया, तथापि सोवियत मंच और पूर्वी यूरोप में एक निश्चित गठबन्धन हो चुका था तथा औपचारिक चीनी सोवियत सम्बन्ध भी अस्तित्व में थे। जहाँ तक अमेरिकी गुट संरचना का प्रश्न है, यह लगभग विश्वव्यापी थी और मात्र भी है। अमेरिकी गुट संरचना का विकास इस प्रकार हुआ¹—

“अमेरिकी राज्यों का संगठन, 1947 (22 सदस्य),
उत्तरी अटलांटिक सन्धि, 1949 (15 सदस्य),
जापान के साथ सुरक्षा सन्धि, 1951 (द्वि-पक्षीय),

फ्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सुरक्षा सन्धि, 1951 (त्रि-पक्षीय),
फिलीपाइन गणराज्य के साथ पारम्परिक प्रतिरक्षा सन्धि, 1951

(द्वि-पक्षीय),

दक्षिण कोरियायी गणराज्य के साथ पारम्परिक प्रतिरक्षा सन्धि, 1953
(द्वि-पक्षीय),

दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा सन्धि, 1954 (आठ सदस्य),

चीनी गणतन्त्र (ताइवान) के साथ पारम्परिक प्रतिरक्षा सन्धि, 1954
(द्वि-पक्षीय)।”

संयुक्तराज्य अमेरिका की सैनिक गतिविधियों के किसी न किसी स्तर पर विश्व के प्रत्येक महाद्वीप की लगभग 45 विभिन्न सरकारों के साथ गठबन्धन था। सन् 1955 के प्रारम्भ में स्थिति यह थी कि जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता केवल 59 सम्प्रभु राज्यों तक सीमित थी वहाँ संयुक्तराज्य अमेरिका और ब्रिटेन एक छोटे तथा सोवियत संघ और अन्य राष्ट्र दूसरी ओर लगभग 60 से भी अधिक राज्यों के साथ संयुक्त थे। यह ध्यान रहे कि कठोर द्वि-ध्रुवीयता से यह आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि दोनों शक्ति-गुट पूरी तरह ‘बराबर’ हों। यह सर्वथा सम्भव है कि द्वि-ध्रुवीयता सैनिक शक्ति में दोनों गुटों के असमान रहने पर भी अस्तित्व में रहे। दूसरे शब्दों में वास्तविक कठोर द्वि-ध्रुवीयता (Actual Tight Bipolarity) और पूर्ण कठोर द्वि-ध्रुवीयता (Perfect Tight Bipolarity) में थोड़ी भिन्नता है।

शिथिल द्वि-ध्रुवीयता—‘बहु-केन्द्रवाद की ओर विकास’

(Loose Bipolarity : Progress Towards Polycentricism)

कठोर द्वि-ध्रुवीयता की स्थिति मंदव बनी रहने वाली नहीं थी, दरार पहले ही पड़ चुकी थी और सताब्दी के पाँचवें दशक के मध्य से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ इस प्रकार की करवट ली, ऐसी नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, नई विचारधाराएँ पनपी और राष्ट्रीय चरित्र या राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठित करने की भावनाएँ बलवती हुई कि पहले की कठोर द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था शिथिल होने लगी। दो महाशक्तियों की गुटोय व्यवस्थाएँ आन्तरिक संघर्षों और सदस्य-राज्यों के पारम्परिक अविश्वास के बढ़ते प्रभाव के कारण ढीली पड़ने लगी। कठोर द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था शिथिल होकर धीरे-धीरे बहु-केन्द्रवाद (Polycentricism) की ओर बढ़ने लगी।

विश्व के द्वि-ध्रुवीय चरित्र को सबसे पहले राष्ट्रीयता की शक्तियों (The Forces of Nationalism) ने चुनौती देना प्रारम्भ किया। यह चुनौती वास्तव में सन् 1948 में ही मिल गई जबकि यूगोस्लाविया ने सफलतापूर्वक सोवियत प्रभाव-क्षेत्र से स्वयं को मुक्त कर लिया। यद्यपि सोवियत यूगोस्लाव-संघर्ष को सैद्धान्तिक संघर्ष का रूप दिया गया तथापि यह एक तथ्य है कि यूगोस्लाविया की राष्ट्रीय

महत्वाकांक्षाएँ ही सोवियत शक्ति के प्रति विरोधी बनीं। सोवियत शक्ति-गुट के लिए जून, 1948 में यूगोस्लाविया का पृथक् हो जाना एक भारी आघात था। स्वतन्त्र विचारों वाले कट्टर राष्ट्रीयवादी मार्शल टीटो यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि सोवियत रूस यूरोप के साम्यवादी शासनतन्त्रों या यूगोस्लाविया पर अपनी कठोर दृष्टि रखे और उन्हें 'लोह-आवरण' (Iron Curtain) में छिपाए रखे। यूगोस्लाविया ने रूसी प्रभाव से मुक्त होकर अपने को पश्चिमी गुट के साथ आबद्ध नहीं किया, वरन् एक स्वतन्त्र और सक्रिय असमर्थ-नीति पर चलना शुरू कर दिया। विश्व की द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था पर यह पहला आघात था जिसके दूरगामी प्रभाव हुए।

रूस और अमेरिका के शक्ति-गुटों में विश्व के जो नवोद्भूत एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुए थे, उन्होंने भी दोनों गुटों से पृथक् रहने की नीति अपनाकर द्वि-केन्द्रीय व्यवस्था को शिथिल बनाया। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भारत की रही। भारत के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री स्व. नेहरू ने कहा कि उनके देश का प्रमुख लक्ष्य है दो विरोधी गुटों के विश्व राजनीति के सागर के दो तटों के बीच एक पुल का निर्माण करना—ऐसा पुल जिसके द्वारा दोनों गुटों की द्वेषों और मतभेदों को दूर करके उन्हें मिलाया जा सके। यद्यपि भारत की यह आकांक्षा नहीं रही कि वह एक तीसरे गुट का निर्माण कर उसका नेतृत्व करे, तथापि अनेक एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों ने भारतीय दृष्टिकोण का अनुसरण किया और इस प्रकार विश्व के द्वि-केन्द्रीय चरित्र को धूमिल बनाने में निर्णायक योग दिया। नामिर का मिस्र और एनक्रुमा का घाना इनमें अग्रणी रहे। धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि लगभग एक-तिहाई विश्व ने यही निर्णय किया है कि दोनों शक्ति-गुटों में से किसी में भी सम्मिलित न हुआ जाए और सक्रिय तटस्थता अथवा असमर्थता की नीति पर चला जाए।

शीघ्र ही दोनों शक्ति-गुटों में और भी शिथिलता आई। पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपना आर्थिक पुनर्निर्माण कर और अपने को पुनः शक्ति-सम्पन्न कर यह चाहा कि अब वे अमेरिकी नीतियों का अन्धानुकरण न करें पर्याप्त अमेरिका के पिछलग्गू बन कर न रहे। यही कारण था कि सन् 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वेज पर आक्रमण किया, यद्यपि रूस की आणविक अस्थो के प्रयोग की घमकी और अमेरिका की नाराजगी के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा लेकिन इस घटना ने हम नथ्य की पुष्टि कर दी कि अमेरिका का नेतृत्व अब शिथिल होने लगा है और पश्चिमी गुट में दरार पड़ने लगी है।

विशेषकर फ्रांस ने, जनरल डिगॉल के नेतृत्व में विश्व की द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था को विशेष आघात पहुँचाया। राष्ट्रपति डिगॉल की प्रमुख चिन्ता सदैव यही रही कि फ्रांस किसी तरह अपने विसृज्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान को फिर से प्राप्त करे। इसीलिए जनै: जनै: वह अपने राष्ट्र को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त करने लगा और दूसरी ओर ब्रिटेन के बढ़ते हुए प्रभाव को भी रोकने की चेष्टा में लगा रहा। इसलिए साम्यवादी देशों के साथ उगने मधुर सम्बन्ध स्थापित किए। साम्यवादी चीन के साथ फ्रांस के

मिनतापूर्ण सम्बन्धों में विकसित हुआ। मास्को की अणु परीक्षण निरोध सन्धि पर हस्ताक्षर न करने वाले केवल दो ही बड़े थे—चीन और फ्रांस। दोनों ही ने यह नर्क दिया कि सन्धि का ध्येय यह है कि सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन अणु शक्तों के क्षेत्रों में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं एवं उनका प्रयोजन यह है कि अन्य देश इस शक्ति का विकास न करने पाएँ।

फ्रांस ने वियतनाम में संयुक्तराज्य अमेरिका की कार्यवाही की निन्दा की, यूरोपीय साम्राज्य बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश को रोकने की डिगॉल की नीति ने पश्चिमी शिविर में फूट का संकेत दिया, संयुक्तराज्य अमेरिका ने बहुत चाहा कि ब्रिटेन को यूरोपीय साम्राज्य बाजार की सदस्यता मिल जाए, किन्तु डिगॉल अपने हठ पर दृढ़ रहे। इतना ही नहीं, निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर इनमें मतभेद नहीं हो सका। जब फ्रांस को संयुक्तराष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग का सदस्य बनाया गया तो उसने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। इससे भी बढ़कर घटना नाटो को पोलरिस अस्त्रों में युक्त करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में पड़ी। सन् 1962 में अमेरिका और ब्रिटेन ने एक समझौते द्वारा यह तय हुआ कि नाटो राज्यों की सेनाओं को पोलरिस प्रक्षेपास्त्रों से लैस किया जाए। फ्रांस ने इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया और निर्णय लिया कि वह इस कार्य में साथ नहीं देगा। सन् 1963 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर देने और दोनों राष्ट्रों के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान हो जाने की घटना से और भी स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति डिगॉल का नाटो-राज्यों से भिन्न अपना अलग ही रास्ता है।

राष्ट्रपति डिगॉल ने समस्त एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त डरावनी है, अन्तर्राष्ट्रीय नम्रता करके इस क्षेत्र का तटस्थीकरण (Neutralisation of S E Asian Region) कर दिया जाए। संयुक्तराज्य अमेरिका और उसके साथ राज्यों ने डिगॉल के सुझाव का कटु-विरोध किया। वास्तव में फ्रांस की ये सभी कार्यवाहियाँ एटलांटिक समुदाय की एकता को मग करने वाली थी। इस एकता को कठोरतम आघात 12 मार्च, 1966 को डिगॉल की इस घोषणा से पहुँचा कि फ्रांस नाटो समूह में अलग होना चाहता है। फ्रांस की माँग पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका को फ्रांस की भूमि पर स्थित नाटो अड्डों को खाली कर देना पड़ा। फ्रांस के नाटो के गरिस्थान के निर्णय से पश्चिमी गुट पर एक महान् सङ्कट आ गया। नाटो में पश्चिमी जर्मनी को सन् 1955 में इस शर्त पर शामिल किया गया था कि वह स्वतन्त्र रूप से अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि नहीं करेगा। इस शर्त के लिए स्वयं फ्रांस बहुत दृढ़ था। परन्तु फ्रांस के नाटो से निःसृत जाने पर पश्चिमी जर्मनी भी इस शर्त से मुक्त हो जाता और तब वहाँ संघ शक्ति में वृद्धि करने का कार्यक्रम जोर-शोर से चलने की सम्भावना हो जाती। पश्चिमी जर्मनी द्वारा सैनिक-शक्ति बढ़ाने के प्रयास की प्रतिक्रिया सोवियत गुट के देशों में होनी और इस तरह हथियारों की होड़ का कुचक्र फिर जोरो से चलना शुरू हो जाता। राष्ट्रपति डिगॉल के इस निर्णय के कारण यूरोप की कूटनीतिक

स्थिति खराब हो सकती थी और पश्चिमी जर्मनी के कारण युद्ध की सम्भावना बढ सकती थी।

ऊपर से विभिन्न दिशाई देने वाले जनरल डिगॉल अपने व्यवहार से राजनीतिक जगत् को चौकाते रहे। कुछ लोगों ने इसे 'वृद्धावस्था की सनक' का नाम दिया। मगर जो लोग इन कार्यवाहियों के उद्देश्य खोजने के पीछे थे उनके अनुसार यूरोप और सम्पूर्ण विश्व के प्रति जनरल डिगॉल का अपना विशिष्ट दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा था—“अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है और स्वभावतः वह अपनी शक्ति बढ़ाने पर तुला हुआ है।” इस शक्ति-विस्तार से बचने के लिए उनके अनुसार दो ही मार्ग थे। पहला मार्ग था कि अमेरिकी गुट का सदस्य बना जाए और यह रास्ता आसान था। दूसरा रास्ता था अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा। इसके लिए यह जरूरी था कि फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के निकट धाएँ अन्यथा अमेरिकी प्रभाव से बच नहीं सकेंगे। इसीलिए फ्रांस और जर्मनी में राजनीतिक घनिष्ठता के लिए सक्रिय कदम उठाए जाते रहे। जनरल डिगॉल का विश्वास था कि फ्रांस ने जिस आर्थिक ढाँचे को पिछले 6 वर्षों में खड़ा किया है, उसे नष्ट न होने दे ताकि उसे अमेरिकी पद्धति द्वारा आत्मसात् न किया जा सके। अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए ही उनकी तीसरी शर्त यह थी कि विश्व में इस बहम को समाप्त कर दिया जाए कि शक्ति के कुल दो ही गुट हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तीसरे गुट के निर्माण के लिए उन्होंने फ्रांस को पूर्वी यूरोपीय देशों के निःकट खाना बाँटा ताकि ‘विश्व-राजनीति में दो गुटों की पद्धति के अतिरिक्त भी कुछ हो।’ इसी नीति को अपनाकर उन्होंने ब्रिटेन के यूरोपीय साभा बाजार में सम्मिलित होने का विरोध किया।

जनरल डिगॉल ने अत्यन्त सदिग्ध और विवादास्पद परिस्थितियों में भी फ्रांस की प्रतिष्ठा का निरन्तर विकास किया। डिगॉल ने अपने राष्ट्रपतित्वकाल में फ्रांस को वास्तव में स्वरित मति से आगे बढ़ाया और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस को जहाँ की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बहुत कुछ प्रसफल चेष्टा की। अप्रैल, 1969 में राष्ट्रपति डिगॉल के शासनकाल के समाप्त होने के बाद न केवल फ्रांस के इतिहास में बल्कि वास्तव में समस्त यूरोप के इतिहास में एक युग का अन्त हुआ। पोलिट्टू नए राष्ट्रपति बने। नई मौखिकी सरकार ने डिगॉल-शासन की धरोहर अपने दृष्टिकोण में कुछ नरमी प्रदर्शित की और हम बान की सम्भावना दिखाई देने लगी कि फ्रांस नाटो का परित्याग नहीं करेगा तथा फ्रांस व मित्र-देशों की सेनाओं में सहयोग की भावना पैदा होगी। यह स्पष्ट हो गया कि फ्रांस ने डिगॉल के नेतृत्व में अपने जिस गृह्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को निष्कार, उसकी वह हर हालत में रखा करेगा। फ्रांस यह नहीं चाहेगा कि एक शक्ति-केन्द्र के रूप में उसका जो उदय हो रहा है वह समाप्त हो जाए।

विश्व की द्वि-भूषीय व्यवस्था को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में हम बान में भी स्थापित पहुँचा है कि अब अणु-प्राप्तियों का एकाधिकार केवल अमेरिका और हम के

पाम हो नहीं रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी अणु-शक्ति के स्वामी बन चुके हैं। यद्यपि इनकी अणु-शक्ति अभी इतनी सम्पन्न नहीं है कि वह अमेरिका अथवा सोवियत संघ की अणु-शक्ति का मुकाबला कर सके और कुछ समय तक आणविक शक्ति का मनुलन अधिक प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है, निश्चय ही ये राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतन्त्र आचरण करते जाएंगे और अमेरिका या रूस के पिछलग्गू कहलाने की स्थिति से बचना चाहेंगे। चीन की महत्वाकांक्षा तो एकदम स्पष्ट हो चुकी है। चीन ने स्वयं को जिस प्रकार सोवियत गुट से एकदम मुक्त कर लिया है और जिस ढंग से साम्यवादी जगत् में सोवियत नेतृत्व की चुनौती दी है, वह आश्चर्यजनक है। साम्यवादी गुट आज दो शक्ति-केन्द्रों में बँट चुका है—एक केन्द्र है रूस तो दूसरा केन्द्र है चीन। रूसी शक्ति को हमरी, पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया के व्यवहार में भी भय पैदा हो चुका है। ये राष्ट्र यद्यपि रूसी मैतिक बल के कारण अपनी आवाज को दबाए हुए हैं, तथापि रह-रह कर प्रस्फुटित होने वाले इनके व्यवहारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में लम्बे समय तक सम्भवतः इन्हें जबरदस्ती सोवियत-शक्ति-केन्द्र के साथ बाँधकर नहीं रखा जा सकेगा अथवा उन पर सोवियत-नियन्त्रण आज के समान कठोर नहीं रह पाएगा।

तेजी से बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हाल ही के कुछ वर्षों से एक नया मोड़ दिखाई देने लगा है और वह है सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य तथा साम्यवादी चीन और अमेरिका के मध्य परस्पर सहप्रस्तित्व की धारणा का विकास। रूस और अमेरिका दोनों ही समझ चुके हैं कि कोई भी अणु-मुद्द विजेता और विजित दोनों के लिए गमन रूप से विनाशकारी गिद्ध होगा। अतः दोनों यह मानने लगे हैं कि अपने सैद्धान्तिक संघर्षों के बावजूद पूँजीवाद और साम्यवाद का सहप्रस्तित्व सम्भव है। रूसी नेता आज ही विस्फोटक परिस्थितियों में यह समझ गए हैं कि साम्यवाद का प्रसार अब शान्तिपूर्ण उपायों से ही करना हितकारी होगा। यद्यपि साम्यवादी चीन का स्वयं अभी तक निराशाजनक रहा है, तथापि 'सम्यता के लक्षण' उगम प्रकट होने लगे हैं। समुक्त राष्ट्रसंघ में उसे स्थान मिल चुका है और कुछ समय से वह सक्रिय और नियन्त्रित आचरण प्रदर्शित करने लगा है। अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर साम्यवादी जगत् के नेतृत्व के लिए सोवियत रूस के लिए उत्कट प्रतियोगी के रूप में उसने अमेरिका की मैत्री के महत्त्व को समझा है। दूसरी ओर साम्यवादी गुट में दरार डालने और क्षीण बनाने का कौशलपूर्ण कूटनीतिक खेल खेलते हुए राष्ट्रपति निकसन ने एक ओर तो रूस मैत्री-सम्बन्ध विकसित किए हैं और दूसरी ओर चीन की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कल का पशु नम्बर एक आज 'मित्र' राष्ट्र की श्रेणी में आने लगा है।

उभरती हुई नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रूपरेखा अभी तक सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है, तथापि यह कहा जा सकता है कि दो शक्ति-गुटों की जगह आज शक्ति या सत्ता के पाँच महत्त्वपूर्ण केन्द्र साफ तौर पर उभर आए हैं। इनमें से दो तो हैं विश्व की महान् शक्तियाँ—अमेरिका और रूस, एवं शेष तीन हैं जापान,

पश्चिमी यूरोप या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश और चीन। एक छठे शक्ति-केन्द्र के रूप में अस्तित्व ग्रहण गृह-निरपेक्ष राष्ट्रों को लिया जा सकता है, पर यह अपेक्षाकृत बहुत कम शक्तिशाली है फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत एक शक्ति-केन्द्र के रूप में तेजी से उभरता जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से भारत अर्द्ध-विकसित देशों की श्रेणी से निकल चुका है तथा सैनिक दृष्टि से उसकी सबलता का प्रमाण विगत वर्षों में मिल चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना-चक्र को प्रभावित करने की भारतीय क्षमता अब सन्देह से परे है। जापान की शक्ति का स्रोत उसकी निरन्तर आर्थिक प्रगति और अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक स्वावलम्बन में निहित है।

कुछ मध्यवर्ती शक्तियाँ भी उल्लेखनीय हैं। ये शक्तियाँ किसी क्षेत्र-विशेष में कुछ समय के लिए चौधरी बन जाती हैं, अतः इनको गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पश्चिमी एशिया में इजरायल एक ऐसी ही मध्यवर्ती शक्ति है।

निरूपण रूप में यह कहना उचित होगा कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहुकेन्द्रीय (Polycentric) है क्योंकि शक्ति के केन्द्र (Centres of Powers) अनेक हैं जिनमें केवल उपर्युक्त 5 या 6 शक्ति-केन्द्र ही नहीं हैं, बल्कि कुछ दृष्टियों से अकेले राष्ट्र और समुक्त राष्ट्रसंघ भी सम्मिलित हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी है कि मीके पर कमजोर से कमजोर एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों की आवाज भी अपना महत्त्व रखती है—विशेषकर क्षेत्रीय मामलों में। वस्तुतः शक्ति-सन्तुलन की ऐतिहासिक परम्परा का आज विशेष महत्त्व नहीं रह गया है और सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की बात प्रव्यावहारिक प्रतीत होने लगी है। आणविक हथियारों की भयकरता ने शक्ति-सन्तुलन के स्वरूप को बदल दिया है और सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की प्रणाली को बहुत कुछ खण्डित कर दिया है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अभी अपनी निर्माणात्मक अवस्था में है और भविष्य में इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने की सम्भावना है। वर्तमान आसार यही हैं कि अभी अनेक महत्त्वपूर्ण शक्ति-केन्द्रों का उदय होना बाकी है। प्राधुनिक विश्व द्वि-केन्द्रीकरण से बहु-केन्द्रवाद की ओर अग्रसर है। फिर भी यह निसर्गिक है कि 'महाशक्तियाँ' तो वस्तुतः केवल दो ही हैं—अमेरिका और रूस और इनमें भी आज अमेरिका शक्ति और सम्पन्नता की दृष्टि से रूस की तुलना में प्रमुख है। दूसरे शब्दों में सत्ता केन्द्रों में अमेरिका का स्थान सर्वोपरि है। दूसरा स्थान रूस का है। आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक मामलों के सन्दर्भ में रूस ही अमेरिका के निकट पहुँच पाता है और इसी कारण उसको 'महाशक्ति' की संज्ञा दी गई है। अमेरिका-रूस सम्बन्ध 'सत्ता केन्द्र गुट' का मूलाधार है। राजनीतिक दृष्टि से इस आधार को ध्वस्त लगाने की सम्भावना निकट भविष्य में बहुत कम है। चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस या भारत अभी इन म्थिति में नहीं आए हैं कि राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका अथवा रूस को प्रतिष्ठा-युक्त कर सकें। एशिया की राजनीतिक शक्ति अभी विभ्रंशित है और पश्चिम

यूरोप की राजनीतिक शक्ति अभी संगठित हो रही है। अतः आज भी चीन, भारत, जापान, जर्मनी या फ्रांस आदि राष्ट्र 'पूर्ण शक्ति' के रूप में उभर नहीं पाए हैं। भारत और चीन अभी सत्ता केन्द्रों में कमजोर हैं। सामाजिक जागृति, अनुशासन और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा लगभग तीस वर्षों के अनवरत परिश्रम के कारण भारत और चीन सत्ता केन्द्र तो बन गए हैं परन्तु दोनों महाशक्तियों के साथ बैठ सकने योग्य नहीं हो पाए हैं। तथ्य यह है कि चीन का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण तो है परन्तु उसके अपने हित सम्बन्ध और क्षमता की दृष्टि से प्रादेशिक सत्ता के हैं। चीन की तुलना में भारत का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विश्वजनीन दृष्टि लिए हुए है तथापि अभी भारत की स्थिति भी प्रादेशिक सत्ता की ही है। कतिपय राजनीतिक क्षेत्रों में यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि अगले दो या तीन दशकों में भारत और चीन महाशक्तियों का स्थान ले लेंगे और अमेरिका तथा रुम 'प्रति महाशक्ति' बन जायेंगे।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अव्यवस्था (International Disorder) अनेक निश्चित और अनिश्चित तत्वों का मिश्रण है जिसमें मुख्य तत्त्व युद्धोपरान्त सोवियत संघ और संयुक्त राज्य के सम्बन्धों में बढ़ती हुई दूरी है। दूसरा मुख्य तत्त्व यह है कि कल के मित्र सोवियत संघ और चीन आज परस्पर शत्रु बने हुए हैं और कल के शत्रु संयुक्त राज्य तथा चीन आज एक-दूसरे की ओर मैत्री के हाथ बढ़ा रहे हैं। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के पारस्परिक सम्बन्धों का ताना-बाना समस्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक जनत को आच्छादित किए हुए है और प्रत्येक महत्वपूर्ण समस्या पर हम इन राष्ट्रों को विभिन्न दिशाओं में विवाद करता हुआ पाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि विशिष्ट परिस्थितियों में समझौते भी हुए हैं, किन्तु अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि युद्धोपरान्त विश्व में जहाँ दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका में भौतिक स्वरूप की विभिन्नताएँ पैदा हो चुकी हैं वहाँ भी दोनों राष्ट्रों के साथ चीन के सम्बन्ध सामान्य और असामान्य रहे हैं और वह दो महाशक्तियों के मतभेदों का पूरा लाभ उठाने की प्रयत्नशील है।

अमेरिका-रूस सम्बन्ध

(U.S.-U.S.S.R. Relations)

आज की दो महान शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस में पैदा जा रहा शक्ति का खेल, विचारधारात्मक ध्रुवता के कारण एक नया महत्व ग्रहण कर चुका है। इन दोनों महाशक्तियों की विदेश नीतियों के उद्देश्यों में मौनिक मध्य से न केवल पराजित शक्तियों से (जर्मनी, जापान आदि) समझौते हो पाने बठिन हो गये हैं बल्कि अनेक देशों में स्थानीय और गृह युद्ध भी होते रहते हैं तथा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ताना-बाना बनता बिगड़ता रहता है। दोनों महाशक्तियों के वैमनस्वपूर्ण सम्बन्धों के कारण शक्ति के ध्रुवीकरण को बन गिरा है। युद्धोपरान्त अमेरिका रूस सम्बन्धों पर दोनों महाशक्तियों की विदेश नीति सम्बन्धी संधियों में बर्बाद हो चुकी की है, यतः यहाँ मोटी रूपरेखा देना ही पर्याप्त होगा—

1. महायुद्ध के उपरान्त रूस और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियों में प्रभुत्व-विस्तार की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। विभिन्न कारणों से सन्देह, अविश्वास और शत्रुता का ऐसा वातावरण बन गया कि ज्ञान्ति-मन्त्रियों का मार्ग कण्टकाकीर्ण हो गया। ज्ञान्ति-प्रयासों के फलस्वरूप यद्यपि ज्ञान्ति-मन्त्रियों सम्पन्न हो गईं लेकिन वे दोनों महाशक्तियों के बीच वैमनस्य और मनभेदों की ऐसी खाई छोड़ गई जिन्हे अभी तक पाटा नहीं जा सका है। तीव्र मनभेदों और अतृप्तमनियों के कारण दोनों शक्ति गुटों में शीतयुद्ध की शुरुआत हो गई।

2. अमेरिका ने इसी प्रभाव और विस्तार को अवरुद्ध करने के लिये 'अवरोध की नीति' अपनाई। इस नीति के अनुपालन में 1947 में ट्रूमैन-सिद्धान्त और मार्शल योजना का आश्रय लिया गया। फलस्वरूप रूस अमेरिका विरोध पहलू की अपेक्षा और भी अधिक उग्र हो गया। मार्शल योजना का उत्पुत्र रूस ने सितम्बर, 1947 में 'कोमिनफार्म' की स्थापना के रूप में दिया।

3. रूस के विरुद्ध सैनिक अवरोध की व्यवस्था को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए अमेरिका ने 1949 में 'नाटो' की स्थापना की। नाटो के जवाब में साम्यवादी देशों को मिला कर रूस ने वारना पैक्ट कायम किया। 1949 में रूस ने एटम बम के रहस्यों को खोज निकाला और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अणुशक्ति पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया।

4. युद्धोपरान्त आधिपत्य के उद्देश्य से कोरिया को अमेरिका और रूस के अन्तर्गत दो खण्डों में विभाजित कर दिया गया। कैपरो घोषणा के अनुसार उम समय में कोरिया को पूर्ण स्वतन्त्रता का वचन दिया गया। सोवियत संघ ने 1948 के आरम्भ में ही कोरिया से अपनी सेनाएँ हटा कर सोवियत खण्ड का प्रशासन वहाँ के साम्यवादियों के हाथ में सौंप दिया और इस प्रकार कोरिया की स्वतन्त्रता का अपना वचन पूरा कर दिया। लेकिन अमेरिका ने अपनी सेनाएँ अमेरिकन खण्ड में बनाए रखी और कोरिया के प्रतिनिध्यावादियों के हाथ में नाममात्र का शासन देकर जापानी कुत्रशासन की परम्परा को बनाए रखा। कोरिया के विभाजन से कोरिया की दोनों सरकारों में गृह युद्ध छिड़ गया। राजनीतिक क्षेत्रों के अनुसार कोरिया-युद्ध एक सुविचारित योजना का परिणाम था। अमेरिका सोवियत संघ को युद्ध में फँसा कर कमजोर कर देना चाहता था। किन्तु जब युद्ध के साथ-साथ समझौता-नीति अपनाई गई और जुलाई, 1953 में युद्ध विराम हो गया। यह स्पष्ट हो गया कि साम्यवादी शक्ति से खुली टक्कर में निर्णायक विजय प्राप्त करना अमेरिका के लिये असम्भव है।

5. मई 1953 में पश्चिमी यूरोप के एकीकरण के सम्बन्ध में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका का शिखर सम्मेलन हुआ। साम्यवाद के अवरोध की अमेरिकी नीति जारी रही और 1954 में सीटो तथा 1955 में बगदाद पैक्ट का सूत्रपात हुआ। 1957 में ब्राइजनहावर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया ताकि मध्य पूर्व में रूसी प्रभाव और विस्तार को रोका जा सके। सोवियत संघ ने इस सिद्धान्त को

अमेरिका की आक्रामक नीति की एक कड़ी माना। आइजनाहावर सिद्धान्त मध्य पूर्व में रूसी प्रभाव को रोक नहीं सका, उल्टे लेबनान तथा जोर्डन में सैनिक हस्तक्षेप के कारण पश्चिम विरोधी तत्त्वों की प्रधानता हो गयी। ईराकी घातिले के फलस्वरूप रूसी प्रभावक्षेत्र बढ़ा। इस सिद्धान्त के कारण दोनों महाशक्तियों में शीतयुद्ध तीव्र हो गया।

6. रूसी श्वेव के नेतृत्व में रूसी लौह आवरण में शिथिलता आने लगी और यात्रा-कूटनीति का आश्रय लिया गया। 1959 के आरम्भ में सोवियत उप प्रधानमंत्री मिखोयान ने अमेरिका की यात्रा की। आपसी वार्ता के दौरान हम बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि दोनों देशों में व्यापार वृद्धि हो, शीत-युद्ध का स्थान शान्ति-पूर्ण प्रतियोगिता से और दोनों ही देश एक-दूसरे के प्रति उदार नीति अपनाएँ। सितम्बर, 1959 में सोवियत प्रधानमंत्री रूसी श्वेव अमेरिका गए पर इनके पूर्व यू-2 विमान-काण्ड घटित हो चुका था और जर्मनी सम्बन्धी विवाद ने भी तूल पकड़ लिया था। अतः रूसी श्वेव की अमेरिका यात्रा भी तनावपूर्ण रही और आइजनाहावर-रूसी श्वेव शिखर सम्मेलन भंग हो गया।

7 तनाव के बावजूद दोनों महाशक्तियाँ परस्पर विचार-विमर्श और संयम का रत्न अपनाएँ रहीं। 1962 में बरूवा-सकट के समय कैंनेडी और रूसी श्वेव दोनों ने विवेक और संयम से काम लिया, फलस्वरूप अणुयुद्ध की घातका टल गयी। परमाणु-शक्ति पर नियन्त्रण और निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर अमेरिका और रूस संयुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर और बाहर विचार-विमर्श करते रहे। सुरक्षा परिषद् में इस सम्बन्ध में जो भी विवाद हुआ उसमें अमेरिका और रूस ने भाग लिया। 1963 में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के बीच एक 'घण्टा-परीक्षण-प्रतिबन्ध सन्धि' सम्पन्न हुई। इस सन्धि से कुछ ही दिवस पूर्व अमेरिका-रूस के बीच 'हाट लाइन एग्जीमैट' भी सम्पन्न हो गया था ताकि विशेष संकट के समय दोनों देशों में सीधा सम्पर्क स्थापित हो सके। जर्मन एकीकरण और बर्लिन के सम्बन्ध में दोनों देशों में मतभेद जारी रहे। सितम्बर 1971 में बर्लिन समझौता सम्पन्न हुआ। दिसम्बर 1971 में भारत-पाक-युद्ध के दौरान दोनों देशों के जहाजी बेडों की हिन्दमहासागर में हलचल हुई, लेकिन दोनों ही देशों ने स्थिति में बिगाड़ नहीं आने दिया। वियतनाम में उलझे रहने के बावजूद दोनों देशों के समझौतावादी रक्त के कारण ही 1972 में पेरिस वार्ता सम्पन्न हो सकी। 1972 में ही कैंनेडी ने मास्को यात्रा की और संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों ने 'शान्तिपूर्ण सम्बन्ध' विवर्धित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अनेक मुद्दों पर दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की जबकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद बने रहे। मास्को-यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परस्पर-परिणीत सन्धि भी सम्पन्न हुई। जून 1973 में ब्रेझ्नेव ने अमेरिका की यात्रा की और दोनों देशों में कुछ समझौते हुए। एक समझौते में दोनों देशों ने संकल्प लिया कि उनमें से कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करेगा। जून 1974 में निकितन मास्को गए और जुलाई 1974 में निःशस्त्रीकरण और अस्त्र परिसीमन की दिशा में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1974 में ही दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण

दन पर्याय व्यापार समझौता हुआ। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध नवम्बर 1975 में विकसित हुए।

8. ग्नाडीवोस्तक में फोर्ड-ब्रेझ्नेव शिखर वार्ता हुई। जुलाई, 1975 में प्रपोनो-सोयुज समुक्त अन्तरिक्ष कार्यक्रम में दोनों ने सहयोग किया। सोवियत मंच और अमेरिका के अधिकारियों में विभिन्न स्तरों पर बातचीत का प्रेम चलता रहा—कभी मास्को में और कभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्तरों पर। जुलाई-अगस्त, 1975 में हेलसिंकी सम्मेलन को सफल बनाने में रूस और अमेरिका ने एक-दूसरे का दृष्टिकोण समझने की कोशिश की। अप्रैल, 1976 में अमेरिका और सोवियत मंच आणविक परीक्षणों का निरीक्षण करने पर सहमत हो गए और मई, 1976 में शांति के लिए परमाणु विस्फोट के आकार आदि पर दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ।

9 1980 के मध्य तक दोनों देशों के सम्बन्ध, बावजूद सामयिक उत्तेजनाओं के, संयम और सुधार का दिशा-मार्ग देते रहे, तथापि सम्बन्धों में उतनी तीव्रता नहीं दिखाई दी जितनी निक्सन और फोर्ड-प्रशासन के दौरान रही थी। क्यूबा में सोवियत मलाहकारों की उपस्थिति, अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के प्रवेश आदि की घटनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच कटुता बड़ी और मनभेद तीव्र हुए, लेकिन दोनों ही पक्षों ने मध्य और सहनशीलता की राजनीति अपनाकर विश्व-शांति बनाए रखने में योग दिया। 8 जनवरी, 1980 को अमेरिका द्वारा 17 हथियों के निष्कासन को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव अधिक बढ़ गया और उसी दिन सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पर रूस ने अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग किया। तथापि 15 जनवरी, 1980 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर दिया। अफगानिस्तान में वहाँ की सरकार के आग्रह पर, सोवियत सैनिक बड़ी मात्रा में टिकी रही तथापि इस मुद्दे पर रूस-अमेरिका के बीच तनाव उतना तीव्र नहीं रहा जितना पहले था। ईराक-ईरान युद्ध में दोनों देशों ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई।

10. जनवरी, 1981 में रीगन द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का पद सम्भालने के बाद से रूस-अमेरिकी सम्बन्ध फिर से तनावपूर्ण बन गए हैं। रीगन अमेरिकी विदेश नीति की अधिकाधिक आक्रामक, विस्तारवादी और हस्तक्षेपवादी बना रहे हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् में तनाव पैदा होने और शीतयुद्ध का वातावरण बनना स्वाभाविक है। रीगन विशाल शस्त्रीकरण की नीति पर चल रहे हैं और अपने पिछलगू देशों को भारी मात्रा में हथियार दे रहे हैं। पाकिस्तान को विशाल सैन्य सामग्री और आधुनिकतम एक 16 विमान देने का निर्णय करके रीगन ने भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव क्षेत्र का विस्तार किया है। जून, 1981 में अमेरिका द्वारा चीन को शस्त्रास्त्र बेचने का भी निर्णय लिया गया। ब्रेझ्नेव के 8 सूची प्रस्तावों के प्रति रीगन का ख़ूबो उपेक्षा का रव था है। नवम्बर, 1981 में सोवियत राष्ट्रपति

बै भनेत्र ने अमेरिका से सभी मुद्रों पर संवाद का आग्रह किया किन्तु रोगन की ओर से सभी स्थिति अनिश्चित है। पोलैण्ड के मामले को लेकर रोगन ने सोवियत संघ के विरुद्ध आधिक प्रतिबन्ध लगाते सम्बन्धी चेतावनी देकर दोनों देशों के सम्बन्धों को अधिक बटु बनाया है। रोगन ने इस तथ्य को नजरअंश कर दिया है कि अलसान्वाडोर आदि सेंटिन अमेरिकी देशों में संयुक्त राज्य कितना नभ हस्तक्षेप कर रहा है। 9 फरवरी, 1982 के समाचारों के अनुसार रोगन द्वारा समायोजित अस्त्रों के उत्पादन को पुन शुरु करने का निर्णय लिया गया है जो विश्व-शान्ति के लिए एक चुनौती है।

अमेरिका-चीन सम्बन्ध
(U. S -China Relations)

राजनीति का यह एक विशिष्ट चरित्र है कि किसी का कोई स्थायी मित्र नहीं होता और न ही कोई स्थायी शत्रु होता है। अमेरिका और चीन पहले एक-दूसरे के घोर शत्रु थे किन्तु अब एक-दूसरे के अधिवाधिक निकट आते जा रहे हैं और हम के विरुद्ध शक्तिशाली 'वाशिंगटन-पेकिंग-पिण्डी-घुरी' का निर्माण त्वरम हो रहा है।

वर्तमान साम्यवादी चीन अथवा चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर, 1949 को हुई। च्यांग-काई-शेक और उसका राष्ट्रवादी दल चीन के एह-युद्ध में साम्यवादियों के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने च्यांग-काई-शेक को वर्षों तक भरपूर सहायता दी, लेकिन माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सेना ने अमेरिका की मनोकामना पूरी नहीं होने दी। च्यांग-काई-शेक ने भाग कर चीन की मुख्य धरती से कुछ ही मील दूर पारमोना द्वीप में शरण लेकर वहाँ चीन की 'निर्वासित सरकार' स्थापित कर ली। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्रसंघ इसी सरकार को अर्थात् राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देने रहे। चीन की मान्यता का प्रश्न 1949 से 25 अक्टूबर, 1971 तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विषय बना रहा। वास्तव में दो चीन की स्थिति कायम रही। दुनिया के लगभग 35 देशों की मान्यता साम्यवादी चीन को प्राप्त थी और 42 देश च्यांग-काई-शेक की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता देने थे। भारत ने प्रारम्भ में ही एक चीन के सिद्धान्त का समर्थन करने हुए साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी थी। आसिर 26 अक्टूबर, 1971 को दो चीन वाली यह स्थिति समाप्त हो गई। संयुक्तराष्ट्र महासभा ने राष्ट्रवादी चीन (ताइवान या पारमोना) को संयुक्तराष्ट्र से निष्काशित कर उसके स्थान पर जनवादी (साम्यवादी) चीन को सदस्य बनाने का प्रस्तावित किया और 35 के विरुद्ध 76 मतों से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 22 वर्ष का यह संघर्ष समाप्त हो गया जो साम्यवादी चीन को विश्व संस्था का सदस्य बनाने के लिए चला रहा था। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इतिहास में यह पहला अवसर था जब संघ के किसी सदस्य और सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य को संघ की सदस्यता से निष्काशित कर उसके स्थान पर किसी अन्य देश को सदस्य बनाया गया हो। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

में चीन का स्वयं सदा आशामक रहा, पर माओ की मृत्यु के बाद नया नेतृत्व कुछ उदार बन रहा है।

चीन-अमेरिका सम्बन्ध (1949-1968) : उग्रवादी नीति

राष्ट्रपति निक्मन द्वारा चीन के प्रति मंत्री का हाथ बढ़ाने से पूर्व दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त शत्रुतापूर्ण थे। अमेरिका ने नवीनित साम्यवादी चीन को न केवल मान्यता देने से इकार कर दिया बल्कि संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रवेश के विरुद्ध भी मोर्चाबन्दी की। अमेरिका की नीति मुख्यतः यह रही है कि साम्यवादी चीन के साथ मंत्री और सहानुभूति रखने वाले देश अमेरिका के मित्र नहीं माने जा सकते। 1950 में कोरिया युद्ध में संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र सेनाओं ने अमेरिकी कमान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। जब संयुक्त सशस्त्र सेनाएँ 38वीं पश्चात् रेखा को पार कर यालू नाम स्थान पर पहुँची तो उत्तर कोरिया की ओर से चीनी सैनिक दिहरी दल की भेजि उन पर टूट पड़े। कोरिया का युद्ध अब प्रधानतः अमेरिका व चीन का युद्ध बन गया। अक्टूबर, 1951 में माओ-त्से-तुंग ने कहा—“हम अपने देश की रक्षा के लिए ही साम्राज्यवादी आक्रमणों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यदि अमेरिकी सेनाओं ने हमारे ताइवान (फारमोसा) पर कब्जा न किया होता और हमारे साम्यवादी मित्र-राज्य पर दक्षिणी कोरिया ने आक्रमण न किया होता तथा स्वयं अपनी कार्यवाहियों का विस्तार हमारी उत्तर-पूर्वी सीमा तक न किया होता तो हम आज अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध लड़ रहे होते।”

कोरिया-युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका ने फारमोसा को साम्यवादी चीन के सम्भावित आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए खुलकर सैनिक सहायता देने का निश्चय कर लिया। अमेरिका के इस निश्चय ने दोनों देशों के सम्बन्धों को और भी अधिक कटु बना दिया। चीन में वाशिंगटन-बिरोधी प्रचार-प्रभियान तीव्र कर दिया गया। क्लाउ बस (Claud Buss) के शब्दों में—“चीनवासियों ने अमेरिका पर जापान में फासिस्टवाद तथा सैनिकवाद की पुनर्स्थापना करने तथा एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जापान का एक साधन के रूप में प्रयोग करने के आदेश लगाए। इसी तरह उन्होंने अमेरिका को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मिगन री की सहायता करने एवं कोरिया में गृह-युद्ध छेड़ने के लिए भी बोली डहगाया।” चीन के साम्यवादी नेताओं ने कोरिया-युद्ध की व्याख्या करते हुए कहा कि—“यह युद्ध कोरिया, फारमोसा, हिन्द-चीन एवं फिलीपाइन्स पर कब्जा करने तथा उसके पश्चात् एशियायी मामलों में हस्तक्षेप करने के अमेरिकी पक्षपात का ही अग्रिम भाग है।”

साम्यवाद के प्रसार की अवरोध करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न सैनिक और प्रतिरक्षात्मक संगठनों का निर्माण किया। अमेरिका द्वारा

निमित्त और प्रेरित नाटो, सीटो, अंजुप्रस (ANZUS), बगदाद पैक्ट (अब सीटो) तथा मध्य-पूर्वी कमान सन्धियों की साम्यवादी चीन ने यह कहकर तीव्र भर्त्सना की कि इन सबका उद्देश्य विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना करना है। अमेरिकियों के लिए चीन की मुख्य भूमि के द्वार बन्द कर दिए गए। अनेक बार तो अमेरिकी पत्रकारों तक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। चीन-स्थित अमेरिकी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई। अमेरिका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध पूर्णतः भंग कर दिए गए। उसके साथ सभी प्रकार के सम्पर्कों पर—चाहे वे सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों या कूटनीतिक हों—रोक लगा दी गई। कोरियाई युद्ध में जिन अमेरिकी चालकों को बन्दी बना लिया गया था, उन्हें भी सोवियत रूस के आग्रह पर बड़े बाद-विवादों के बाद मुक्त किया गया।

1954 में हिन्द-चीन के प्रश्न पर भी दोनों देशों में काफी तनाव पैदा हो गया। डीन-विन-पू मे फ्रेंच सेनाओं की निर्णायक पराजय के उपरान्त जब वाशिंगटन ने फ्रांस की सहायतायें भारी सख्या में अपनी सेनाएँ भेजने का निश्चय किया तो अमेरिका और साम्यवादी चीन में प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा हो गया। सोभाग्यवश जिनेवा सम्मेलन सम्पन्न हो जाने के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति टल गई। 1959 में चीन और अमेरिका के बीच सघर्ष के नए कारण उत्पन्न हो गए। लाओस में सघर्ष के लिए चीन ने अमेरिका को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि वह वियतनाम के प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य एवं चीन की सुरक्षा को सीधे चुनौती देने के लिए ही सुदूर पूर्व में सघर्ष चाहता है। तिब्बत की कान्ति के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के रवैये से भी चीन को भारी क्षोभ हुआ। इसके अनिर्दिष्ट जनवरी, 1960 में जापान तथा अमेरिका के बीच जो पारस्परिक सहयोग एवं सुरक्षा की सन्धि सम्पन्न हुई, उससे भी चीन के सम्बन्ध कटु बने। चीन ने हर सम्भव प्रयत्न द्वारा जापान व अमेरिका के गठबन्धन को निरस्त करने का प्रयास किया। पीकिंग रेटियो ने अमेरिका पर एशिया में साम्राज्यवादी पड़्यन्त्र रचने का आरोप लगाया। 9 सितम्बर, 1962 को साम्यवादी चीन की वायु सेना के एक डू-2 सैनिक जॉब नायुमान को चीन की मुख्य भूमि पर गार गिराया। चीन सरकार ने इस घटना पर एक विस्तृत वक्तव्य प्रसारित किया और अमेरिका को इस विमान की उड़ान के लिए उत्तरदायी ठहराया। अक्टूबर, 1962 में 'क्यूबा-सनट' के समय साम्यवादी चीन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध भारी विप-बमन किया गया। सम्पूर्ण चीन में क्यूबा समर्थक विशाल प्रदर्शन सगठित किए गए, क्यूबा समर्थक नारे लगाए गए और क्यूबा के नेताओं के चित्रों का प्रदर्शन किया गया। 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत को जो प्रभावशाली सैनिक सहायता भेजी, उससे भी साम्यवादी चीन के आशंका में वृद्धि हुई।

1965-66 में वियतनाम-समस्या के प्रश्न पर दोनों देशों के सम्बन्धों में बहुतों में और भी वृद्धि हुई। वियतनाम में शान्ति-स्थापना के हर प्रयाग को चीन ने असफल बनाने की कोशिश की। चीन की प्रेरणा से ही उत्तर-वियतनाम ने सभी

शान्ति प्रस्तावों के विरुद्ध कठोर रुब आना शुरू हुए केवल अपने ही प्रस्ताव को मानने पर बल दिया। जब हनोई सरकार शनैः-शनैः पीकिंग की अपेक्षा मास्को के अधिक निम्न आने लगी तो यह भी चीन को बुरा लगा और उसका प्रयत्न यही रहा कि हनोई चीन के मैनिक निर्देशन में दक्षिण विषयनाम से मुद्धरत रहे।

राष्ट्रपति जॉनसन ने भी साम्यवादी चीन को मान्यता देने से इंकार कर दिया। वे यह मानते रहे कि जिस लाख चीन ने आज तक हिंसा और युद्ध का सहारा लिया है, संयुक्त राष्ट्रमण्ड से युद्ध किया है, विजय की स्वतन्त्रता का अपहरण किया है और जो अमेरिका के विनाश की बात करता है, उसे नए में प्रवेश के योग्य एक शान्तिप्रिय राष्ट्र नहीं माना जा सकता तथा अमेरिका उसे मान्यता नहीं दे सकता।

1966 तक चीन-अमेरिकन पारस्परिक विरोध की भावनाओं में परिवर्तन नहीं हुआ। ताइवान और विषयनाम सम्बन्धी प्रश्न दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण थे। अमेरिकन विदेश मन्त्री डीन रस्क और चीनी प्रधान मन्त्री चाउ-एन-लाई के दो वक्तव्यों ने हमें स्पष्ट रूप से पता चलना है कि दोनों देशों की एन-डूमेरे के प्रति क्या नीति थी, दोनों राज्य पारस्परिक विरोध की भावनाओं से कितना ग्रस्त थे —

अमेरिकन विदेश मन्त्री डीन रस्क ने 16 मार्च, 1966 को अपने एक वक्तव्य में चीन के प्रति अमेरिकन नीति का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित 10 मुख्य सूत्रों का वर्णन किया—

प्रथम, अमेरिका को उन राष्ट्रों की सहायता करने के लिए, जो चीन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी और बल प्रयोग का विरोध कर पाने के लिए, अमेरिका की सहायता मांगते हैं, दृढ़ निश्चय रहना चाहिए।

द्वितीय, अमेरिका को एशिया में गैर-साम्यवादी सरकारों की स्थापना और समर्थन करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए।

तृतीय, ताइवान के प्रति अपने वचन पूरे करने चाहिए और चीन को भी ताइवान क्षेत्र में बल प्रयोग का त्याग कर देना चाहिए।

चौथे, संयुक्त राज्य को संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता का विरोध करते रहना चाहिए।

पाँचवें, चीन के साथ युद्ध का भय होते हुए भी अमेरिका चीन पर आक्रमण करना नहीं चाहता।

छठे, चीन की नीति में कभी परिवर्तन या रसकता है और संयुक्त राज्य को दोनों देशों में निश्चल और स्थायी विरोध की स्थिति को महत्त्व नहीं देना चाहिए।

सातवें, साम्यवादी चीन के साथ गैर-सरकारी सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे धीरे-धीरे संयुक्त राज्य के प्रति पीकिंग के विचारों में परिवर्तन आ सके।

आठवें, वारसा में अमेरिका को चीन के साथ प्रत्यक्ष द्वितीयक सम्बन्ध बनाए रखने चाहिए।

नवें, अमेरिका, पीकिंग और अन्य देशों के साथ मिलकर निःशस्त्रीकरण और परमाणु शस्त्रों के अत्यधिक उत्पादन पर रोक लगाने की गम्भीर समस्याओं पर विचार करने के लिए तत्पर है।

दमवें, अमेरिका की सरकार को साम्यवादी चीन से सम्बन्धित सूचना को दूढ़ने और उसके विश्लेषण के प्रयत्न में रहना चाहिए। जब पीकिंग बल-प्रयोग को त्याग देता है और संयुक्त राज्य के प्रति विरोध समाप्त करने को तैयार हो जाता है तो 'दोनों' में विस्तृत और सुधरे हुए सम्बन्धों की सम्भावना हो सकती है।¹

डीन रस्क के इस वक्तव्य के प्रति चीन सरकार की प्रतिक्रिया भी विरोध की ही थी। 1 अप्रैल, 1966 के 'पीकिंग रिव्यू' ने आरोप लगाया कि 16 वर्ष से अमेरिकन साम्राज्यवाद चीन के प्रति विरोध की नीति अपनाए हुए है, उसने बलपूर्वक चीनी क्षेत्र 'ताइवान' पर कब्जा कर रखा है, चीन के विरुद्ध नौ-सैनिक शक्ति तैनात कर रखी है और चीन में विध्वंसकारी कार्यवाहियों के लिए गुप्त एजेंट भेज रहे हैं, पत्र में कहा गया—“संयुक्त राज्य साम्राज्यवाद की कार्यविधियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह चीन के लोगों का बहुत बड़ा शत्रु है। चीन के प्रति संयुक्त राज्य सरकार की नीति ट्रूमैन और आइज़नहावर के समय से लेकर कनेडी और जॉनसन प्रशासन तक वही रही है। वर्तमान जॉनसन प्रशासन ने भी आक्रमण और चीन के प्रति विरोध की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया है। वास्तव में अब इस नीति का पालन अधिक कठोरता और निलंजिता से किया जा रहा है। यह सार्वजनिक घोषणा की जा चुकी है कि चीन संयुक्त राज्य का मुख्य शत्रु है। अमेरिका ने अपनी विश्व-नीति का प्रभाव क्षेत्र अब एशिया में बना दिया है और चीन के घेराव के लिए सैनिक गतिविधियों को तीव्र कर दिया है। वियतनाम के युद्ध को चीन की ओर लाने का भी बहुत गम्भीरता से प्रयत्न किया जा रहा है। उच्च अमेरिकन सैनिक और नागरिक अधिकारी चीन के साथ शक्ति-परीक्षण की बात खुलेआम कर रहे हैं। जॉनसन प्रशासन के कहने और करने में अत्यधिक विभिन्नता है।”

चीन ने आरोप लगाया कि विश्व के सभी भागों में चीन के प्रति घृणा का प्रचार किया जा रहा है। 'चीन-विरोधी मोर्चे' में संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवादी, गोविषय मशोघनवादी, जापानी सैन्यवादी और भारतीय प्रतिस्पर्धावादी सम्मिलित हैं। तत्कालीन चीनी प्रधान मन्त्री चाउ-एन-लाई ने अमेरिका के प्रति अपने देश की नीति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य में कहा—

“(1) चीन संयुक्त राज्य के साथ युद्ध छेड़ने में पहल नहीं करेगा। चीन ने हवाई (Hawaii) में कोई सेनाएँ नहीं भेजी हैं जबकि संयुक्त राज्य ने ताइवान प्रदेश पर कब्जा कर दिया है फिर भी चीन इस सघर्ष को वार्तालाप द्वारा सुलझाने के पक्ष में है। (2) चीन के लोग जो महमूग बरते हैं, वही कहते हैं। यदि एशिया,

पफोका या किसी अन्य देश के किसी भाग पर साम्राज्यवादियों द्वारा आक्रमण किया गया तो चीन की सरकार उसे अवश्य ही सहायता और आश्रय प्रदान करेगी। यदि इस न्यायोचित कार्य से संयुक्त राज्य चीन पर भी आक्रमण कर दे तो वह बिना हिचकिचाहट के उसका भी मुकाबला करेगा और अन्त तक युद्ध करता रहेगा। (3) यदि संयुक्त राज्य चीन को युद्ध के लिए मजबूर करता है तो चीन उसके लिए भी तैयार है। चाहे संयुक्त राज्य कितने ही सैनिकों को भेज दे और परमाणु तथा कैंम भी अस्त्रों का प्रयोग कर ले, चीन के लोग संयुक्त राज्य की सेनाओं को वापिस जाने नहीं देंगे। यदि वियतनाम के 14 लाख लोग संयुक्त राज्य के दो सौ सहस्र लोगों का मुकाबला कर सकते हैं तो चीन के 650 लाख लोग निश्चिततया ही अमेरिका के दस लाख सैनिकों का सामना कर पाएँगे। (4) एक बार युद्ध आरम्भ हो जाने पर, फिर उसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकेगी। कुछ संयुक्त राज्य योजना-निर्माता नाविक और वायु उच्चता से चीन पर बम्ब गिराकर स्थल युद्ध से बचना चाहते हैं। यह तो केवल विचार ही है। एक बार वायु या जल की दिशा से युद्ध आरम्भ हो जाए तो फिर यह निर्णय केवल संयुक्त राज्य के हाथ में ही नहीं होगा कि युद्ध किस प्रकार जारी रखा जाएगा। यदि अमेरिका की सेनाएँ आक्रान्त की ओर से आती हैं तो उनका प्रत्युत्तर चीन स्थल-युद्ध से क्यों नहीं दे सकता? यह संयुक्त राज्य को स्पष्ट चेतावनी थी कि चीनी क्षेत्र पर संयुक्त राज्य द्वारा बम्ब गिराये जाने का अर्थ होगा कि चीन स्थानीय शक्ति द्वारा इन्डोचीन संपर्क में हस्तक्षेप आरम्भ कर देगा।¹

चीन-अमेरिका विरोध पर अपनी टिप्पणी और फॉरबैंक तथा टेलर के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए डॉ. मिथ एव सत्रा ने लिखा है—इन विवादों के विनिमय की अपेक्षा भी चीन और संयुक्त राज्य ने एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध आरम्भ नहीं किया। फॉरबैंक और टेलर (Fairbank and Taylor) ने 1960 के दशक में चीन की नीतियों के दो विभिन्न परीक्षण किए। फॉरबैंक का कहना था, कि चीनी साम्यवादी मुख्यतः चीनी ही थे और अपनी प्रशासनिक परम्पराओं के प्रति बफादार थे। टेलर का विचार था कि वे मुख्यतः साम्यवादी थे और उनमें राष्ट्रीयता के कोई गुण नहीं थे। फॉरबैंक ने इस बात पर बल दिया कि चीन में जातीय तत्त्व शक्तिशाली थे और विश्व-क्रान्ति में अधिक योगदान नहीं दिया जा रहा था। टेलर ने इस विचार से इंकार किया और कहा कि साम्यवादी विश्व बहुकेन्द्रीय बन रहा था। फॉरबैंक ने चीन के विस्तारवाद को न मानते हुए मामों के विश्व-क्रान्ति के कार्यक्रम को साहित्यिक ही बताया। टेलर ने लिन पीओ (Lin-Piao) की विश्व-क्रान्ति की पुकार और चीन द्वारा तीसरे विश्व-देशों में वियतनाम जैसे उपद्रव छेड़ देने की धमकी को गम्भीरता से लिया। टेलर साक्षात्कार की नीति को बनाए रखना चाहता था। फॉरबैंक का सुझाव था कि चीन के प्रति अमेरिका की नीति पर फिर से

विचार किया जाए और विघटनार्थक प्रति समझौता, पीपिंग शासन की मान्यता, संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता और ब्यांग-काई-शेक शासन की आश्रय देने की समाप्ति इसके लिए आधारभूत रखे जाएँ। उसने याद दिलाया कि "हम अमेरिकन, आधुनिकता की योगदान देने का महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे होने के कारण चीन-अमेरिकन सम्बन्धों में अधिक लाभ की स्थिति में रहे हैं। यह विशेष स्थिति सन्धिपों द्वारा प्राप्त कर लेने पर बहुत से अमेरिकन इन सम्बन्धों का विशेष लाभ उठाते रहे हैं। उन्हें उच्च-वर्गीय विदेशी माना जाता था जो कि अभी भी मौलिक रूप से लोकतन्त्रीय होते हुए भी रिश्ते में सवारी करता था और उच्च स्थिति की सुविधाएँ भी प्राप्त करता था।" कैररदैक ने चीन अमेरिकन सम्बन्धों में सुधार और जानकारी लाने के लिए इन दोहरे स्तरों को समाप्त करने की माँग की।

चीन अमेरिका सम्बन्ध (1969-1982) :

तनाव जैथिल्य की ओर प्रगति

20 जनवरी, 1969 रिचार्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति बने। निक्सन ने ऐसे प्रयत्न आरम्भ किए जिनका उद्देश्य चीन से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करना था ताकि एक ओर तो विघटनार्थक युद्ध से अमेरिका समझाने पीछा छोड़ सके और दूसरे सोवियत प्रभुत्व को मकल चुनौती देते हुए राजनीतिक क्षेत्र में पौकिंग-पिण्डो-वाशिगटन घुरी का निर्माण कर, शक्ति-सन्तुलन अपने पक्ष में कर ले। अमेरिका को यह लानमा भी रही कि लगभग 70 करोड़ की विशाल जनसंख्या वाले देश में मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करके अमेरिका व्यापक व्यापारिक और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेगा। चीन की भी यह आकांक्षा थी कि सोवियत हम के नेतृत्व से चुनौती देने के लिए वह अमेरिका जैसे सत्र राष्ट्र को अपने पक्ष में कर ले।

संयुक्त राज्य और चीन पर 'आगामी दशक' (Next Decade) नामक प्रथम राष्ट्रीय समारोह न्यूयार्क में 20-21 मार्च, 1969 को हुआ। लगभग 2500 व्यक्तियों ने, जिनमें चीन के विभिन्न श्रेणियों के विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे, इस समारोह में भाग लिया। उन्होंने पुरानी नीति का पुनः परीक्षण किया और नए निर्देशों का सुझाव दिया। एडवर्ड कनेडी ने समारोह में घोषणा की—“पिछले दोम वर्षों में चीन के प्रति हमारी नीति मुझ की नीति ही रही है। हमने बहुत देर में विश्व के एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक विरोध की नीति अपनाई है। अब हम अपनी युद्ध की नीति छोड़ कर शांति की नीति अपनानी है। अब हमें एक नई नीति ढूँढनी है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी वर्तमान स्थिति में कोई कमजोरी है या हम चीन के प्रति नम्र हो गए हैं, परन्तु इसलिए कि ऐसा करना हमारे तथा अन्य सभी राष्ट्रों के हित में है।”

सम्बन्ध सुधार में प्रयत्न शुरू हुए और चीन-अमेरिका के बीच 'विगपोंग कूटनीति' का उदय हुआ। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार, यात्रा और जहाजरानी सम्बन्धी राखूनी खानदों में डीन दे दी तथा अपनी टेक्नॉलॉजी टीम को विगपोंग

मेलने के लिए चीन भेजा। 1970 में माओ-स्ने-तुंग ने अमेरिकी पत्रकार एडगर स्नो के साथ वानचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत चीन में करने की इच्छा प्रकट की। दोनों देशों में सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु वारमा, पेरिस आदि स्थानों पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्ताओं का दौर आरम्भ हुआ जिनकी प्रगति के आधार पर 15 जुलाई 1971 को बहुत ही नाटकीय ढंग से राष्ट्रपति निक्मन में मई, 1972 के पूर्व अपनी चीन यात्रा की घोषणा की। भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने इस घोषणा का स्वागत किया और समुक्त राष्ट्रमण्डल के महासचिव ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में एक नया अध्याय प्रारम्भ करने वाली घटना बनलाया। 21 फरवरी 1972 को राष्ट्रपति निक्मन दलबल सहित पीकिंग पहुँचे। संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देशों में अनेक विषयों पर मतभेदों के बावजूद सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। दोनों देशों ने ज्ञान और कला के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक विनिमय और सम्पर्क का निश्चय किया। आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि पर भी विचार-विमर्श किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि सामान्य हित के विषयों पर विचार-विनिमय और सम्बन्धों के सामान्यीकरण के लिए विभिन्न माध्यमों से अधिकाधिक सम्पर्क स्थापित किया जाए। निक्मन की पीकिंग यात्रा के बाद दोनों देशों के सम्बन्ध तेजी से सामान्य बनते गए। वगला देश के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्रमण्डल में दोनों ने आपस में सहयोग किया। फरवरी 1973 में निक्मन के निजी सलाहकार हेनरी किंसिंगर ने पीकिंग में चार्ल-एन-लाई तथा अन्य नेताओं से वार्ता की। अमेरिका और चीन द्वारा एन-हूमेरे के यहाँ सम्पर्क कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया। यद्यपि इन कार्यालयों को इनावास की सजा नहीं दी गयी तथापि व्यवहार में इतना कार्य इनावास जैसा ही चला गया। दोनों देशों के बीच अनेक क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि हुई। पारस्परिक व्यापार विस्तार का एक निश्चित कार्यक्रम बनाया गया। चीन अमेरिका के दो बन्दी वायुयान-चालकों को मुक्त कर और अमेरिका ने ताइवान में अपनी सेना में पर्याप्त कटौती का संकेत देकर यह प्रदर्शित किया कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों देश अधिकाधिक निकट आने को उत्सुक हैं।

दोनों देशों के सम्बन्धों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया तब कुछ मन्द हो गयी जब चीन ने देखा कि अमेरिका रूस के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने के प्रयत्नों में महत्त्वपूर्ण विषयों पर वार्ता में चीन की उपेक्षा कर रहा है। नवम्बर 1974 में जब अमेरिकी विदेश मंत्री डॉ. किंसिंगर चीन गए तो उनके स्वागत में उदासीनता प्रकट कर चीनी नेताओं ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की। इस अप्रसन्नता के दो प्रमुख कारण थे—अमेरिका द्वारा ताइवान सम्बन्धी उस जघाई समझौते को कार्यान्वित न किया जाना जो साल भर पहले दोनों के बीच हुआ था, एवं अमेरिका राष्ट्रपति कोर्ड गीर मोदियत नेता ब्रेझ्नेव द्वारा वार्ता के लिए व्नाडीवास्टोक को चुनना। व्नाडीवास्टोक कभी चीन का हिस्सा था अतः चीन ने सोचा कि उसे चिढ़ाने के लिए इसे वार्ता-स्थल चुना गया है। 1972 की जघाई विज्ञप्ति में किए गए वायदों में एक महत्त्वपूर्ण वायदा यह था कि अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मान लेगा। अग्रेज, 1975

च्यांग-काई-शेक की मृत्यु के बाद ताइवान अब फिर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रारंभ केन्द्र बन गया। मार्ग-च्यौंग के निधन का न केवल ताइवान की प्रान्तरिक राजनीति पर बल्कि अन्य देशों के सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। वैसे च्यौंग के उत्तराधिकारी उनके पुत्र प्रधानमन्त्री च्यौंग-चुंग-कुमो ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने देश पर कभी भी साम्यवाद की छाया नहीं पड़ने देंगे और चीन की मुख्य भूमि को साम्यवाद से मुक्त करने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहेंगे।

निकसन के हटने के बाद से ही अमेरिका और चीन के सम्बन्धों में कुछ स्थितिगत उत्पन्न हो गयी। जैसा कि अमेरिकी विदेश नीति के सन्दर्भ में बताया जा चुका है, जब डॉ. किमिंगर ने अक्तूबर, 1975 में और राष्ट्रपति फोर्ड ने दिसम्बर, 1975 में चीन की यात्रा की तो उनका बहुत ही पीका स्वागत हुआ।

निकसनकाल में अमेरिका-चीन सम्बन्धों का मूल्यांकन करते हुए डॉ. मिश्र एवं खन्ना ने लिखा है कि निकसन प्रशासन ने किमिंगर की व्यक्तिगत कूटनीति का प्रयोग करते हुए 1970 के दशक में चीन-अमेरिकन सम्बन्धों की नींव रखी। संयुक्त राष्ट्र ने 'दो चीन' की नीति त्याग दी, पीकिंग को चीन की वैधिक सरकार के रूप में मान्यता दी, संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता का समर्थन और सुरक्षा परिषद् में स्थायी स्थान दिए जाने का वचन दिया। ताइवान से सेनाएँ निकाल लिये जाने की स्वीकार कर दिया गया विपतनाम संधि के मुद्दाव के लिए वार्तालाप की स्वीकृति दे दी। अन्य ये दक्षिणी विपतनाम ने अपनी सेनाएँ पूर्णतया हटा लेने का वचन दिया। धीरे-धीरे सभी इण्डोचीन राज्यों से अमेरिकन प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया और दक्षिणी विपतनाम, कम्बोडिया और फिर लाओस में साम्यवाद पक्षीय शासन स्थापित हो गए। जापान और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य अमेरिकन साथी देशों ने चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित कर लिए। चीन के साथ साक्षात्कार की अमेरिकन नीति तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में हस्तक्षेप से संयुक्त राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ।

20 जनवरी 1977 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जिम्मी कार्टर चारुड हुए। अगस्त 1977 में विदेश मन्त्री साइरस वेन्स ने चीन की यात्रा की। ताइवान सम्बन्धी मतभेद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय सहयोग के अन्य मुद्दों पर मतभेद नहीं हो सका। कुन मिलाकर यह यात्रा दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधार में सहायक नहीं हुई। इसके बाद कार्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिम्मी ने फोर्गि की यात्रा की। कार्टर ने चीन के प्रति अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और चीन को विभिन्न विस्मों के हथियारों तथा विद्युत घाणविक उपकरणों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों में छीन देने का निश्चय किया। ताइवान के प्रश्न पर मतभेद घटने गए और 1 जनवरी 1979 को कार्टर ने चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की। कार्टर ने अपने वक्तव्य में यह मान लिया कि चीन केवल एक है और उसी एक सरकार है, तथापि यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका गैर-सरकारी तौर पर ताइवान से सम्बन्ध रख सकता है।

दोनों पुराने शत्रु देश एक दूसरे के निकट आते गए और फरवरी 1979 में डेंग विनझाओ पिंग अमेरिका की यात्रा पर गए। डेंग-कार्टर-संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि चीन एवं अमेरिका किसी एक देश या कुछ देशों के समूह द्वारा अन्य देशों पर आधिपत्य या बन्धनकारी शक्ति स्थापित करने के विरुद्ध है। स्पष्ट था कि यह वक्तव्य रूस को ध्यान में रखते हुए दिया गया। अमेरिका ने फ्रांस द्वारा चीन को प्रणुशक्ति यन्त्र दिए जाने का समर्थन किया। चीन ने अमेरिका की विश्वव्यापी सैनिक गतिविधियों को स्वीकार किया और अमेरिका ने भी विश्वास प्रगट किया कि शक्तिशाली तथा सुरक्षित चीन विरुद्ध-सम्बन्धों में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। जुलाई 1980 में टोकियो में राष्ट्रपति कार्टर और प्रधानमंत्री हुआ कुमो फेग ने पहली बार वार्ता हुई। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध दोनों देशों ने एक स्वर से किया। कार्टर ने एक दूरदर्शन भेटवार्ता में कहा कि रूसी सैनिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका-चीन और जापान को एक हो जाना चाहिए। यद्यपि चीन के प्रति अमेरिकी नीति में परिवर्तन बहुत पहले हो गया था और दोनों देशों के बीच अभी तक व्यापारिक तथा अन्य असेैनिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता जा रहा था लेकिन सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिए यह नया सहयोग दोनों देशों को सैनिक क्षेत्रों में भी ले आया। इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि सोवियत संघ ने यदि कोई जवाबी कार्रवाही की तो अन्ततः एशिया की शान्ति खारे में पड़ जाएगी। 20 जनवरी 1980 को रीगन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। रीगन प्रशासन के दौरान 1982 के प्रथम चरण तक दोनों देशों के सम्बन्ध लगभग बने ही हैं जैसे कार्टर प्रशासन के दौरान थे। 'वाशिंगटन-पीकिंग-पिण्डी घुड़ी' को रीगन प्रशासन ने और शक्तिशाली बनाया है तथा इस बात के भी आसार स्पष्ट हैं कि निकट भविष्य में रूस के विरोध में 'वाशिंगटन-टोकियो-पीकिंग-पिण्डी-घुड़ी' शक्तिशाली रूप में अस्तित्व में आ जाएगी।

सोवियत-संघ और चीन के सम्बन्ध : चीन-सोवियत संघर्ष (U.S.S.R. & China Relations : Sino-Soviet Conflict)

सोवियत संघ और चीन—इन दो महान् साम्यवादी राष्ट्रों के सम्बन्ध मैत्री और शत्रुता, सहयोग और स्पर्धा, भाईचारे और कटु-वैमनस्य की कहानी रहे है। 1 अक्टूबर, 1949 को साम्यवादी चीन की स्थापना के तुरन्त बाद रूसी-चीनी-मैत्री तेजी से बिजसित हुई, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद दोनों के बीच साम्यवादी जगत् के नेतृत्व के लिए तीव्र स्पर्धा छिड़ गई, विभिन्न प्रश्नों पर सैद्धान्तिक मतभेद उग्र हो गए, सीमा-विवाद उठ खड़े हुए और सशस्त्र सीमा संघर्ष भी हुए। आज स्थिति यह है कि एक ओर तो चीन और अमेरिका, जो एक-दूसरे के घोर शत्रु थे, रूसी शक्ति के विरुद्ध अपने हाथ मिला रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका और रूस सह-अस्तित्व और सहयोग की बात करते हुए चीन की विस्तारवादी अतर्काक्षायी पर प्रकुश लगाते

को सचेष्ट हैं। रूस-चीन-अमेरिका का यह त्रिकोणात्मक संघर्ष विश्व-राजनीति में शान्तिकारी परिवर्तन ला रहा है।

रूस-चीन में सहयोग का काल

चीन के जनवादी गणतन्त्र की स्थापना होते ही सोवियत रूस ने उसे अपनी मान्यता दी और माघो-त्से-तुंग ने फरवरी, 1950 में रूस की यात्रा कर 24 फरवरी को दोनों देशों के बीच तीन सन्धियाँ सम्पन्न की—(1) 30 वर्ष के लिए मंत्री और पारस्परिक सन्धि, (2) चाँगच्यांग रेल्वे, पोर्ट आर्थर तथा दाइरन से सम्बद्ध सन्धि, एवं (3) ऋण सम्बन्धी सन्धि। प्रथम सन्धि के अन्तर्गत जापानी शयवा उसके सहयोग से किसी भी विदेशी आक्रमण की स्थिति में दोनों देशों में एक-दूसरे की सहायता करने तथा साथ ही पारस्परिक हितों पर आँच लाने वाली किसी भी सन्धि में शामिल न होने का निश्चय किया। जापान के साथ शान्ति-सन्धि के लिए प्रयास करने, समान हितों के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर आपसी विचार-विमर्श करते रहने तथा पारस्परिक निकटतम आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने पर भी सहमति प्रकट की गई। द्वितीय सन्धि द्वारा सोवियत संघ ने च्यांग चुन-रेल्वे को जापानी शान्ति-सन्धि के बाद और अधिक से अधिक 1952 के अन्त तक चीन को हस्तान्तरित करने का वचन दिया। यह भी निश्चित हुआ कि 1952 तक सोवियत संघ की सेनाएँ पोर्ट आर्थर से वापस बुला ली जाएँगी। तृतीय सन्धि द्वारा सोवियत संघ ने चीन को 5 वर्ष की अवधि के लिए 3 करोड़ डॉलर का ऋण देना स्वीकार किया। इस ऋण को 5 किश्तों में दिया जाना तथा 31 दिसम्बर, 1954 के पश्चात् 10 किश्तों में लौटाया जाना निश्चय हुआ।

सन्धियों के सम्पन्न होने के उपरान्त कुछ वर्षों तक रूस-चीन मंत्री विक्रमित होती रही। सितम्बर, 1952 में च्यांग चुन-रेल्वे चीन को लौटा दी गई, परन्तु पोर्ट आर्थर के बारे में यह निश्चय हुआ कि वह तब तक नहीं लौटाया जाएगा जब तक रूस और चीन के साथ जापान की शान्ति-सन्धि नहीं हो जाती। बाद में 1954 में यह तय किया गया कि पोर्ट आर्थर 1955 में चीन को दे दिया जाएगा। मई, 1955 में इसे चीन को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस अवधि में सोवियत संघ द्वारा चीन को दी जाने वाली वित्त, वाणिज्य और प्राविधिक सहायता में भी निरन्तर वृद्धि होती गई। चीन का लगभग 70% व्यापार रूस के साथ होने लगा जिसमें 1950 के बाद निरन्तर वृद्धि होती चली गई। 1954 में ही रूस ने चीन को अणुशक्ति-उत्पादन में भी सहयोग देना स्वीकार किया, परन्तु साथ ही यह निर्णय भी हुआ कि चीन द्वारा रूस की पूर्ण अनुमति के बिना अणु-परीक्षण नहीं किया जा सकेगा। इसके अनुरिक चीनी-रूसी मंत्री-मण्डल स्थापित किए गए।

सोवियत संघ ने चीन की संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्थान दिलाने के लिए निरन्तर प्रयास किया। 1954-55 में दोनों देशों ने पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका स्थापित प्रादेशिक मंत्रि मण्डलों की बहु ध्यानीयता की। 1956-57 में

दोनों ने मिल कर ब्रिटेन व फ्रांस के घात्रमण की निन्दा की। हंगरी और पोलैण्ड में जब दक्षिण-पंथी दंगे हुए तब भी दोनों देशों में नियमित रूप से विचार-विमर्श होते रहे। 1958 में टोटो के सशोधनवाद की कटु प्रालोचना भी दोनों ही देशों द्वारा की गई। सोवियत संघ की भाँति ही अन्य समाजवादी देशों के साथ चीन ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रखे।

रूस-चीन में मतभेद और कटु वैमनस्य का काल

रूस और चीन के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में तनाव का बीजारोपण 1954 में ही स्पष्ट हो गया। सोवियत-साम्यवादी दल की 23वीं कांग्रेस में श्री ए.इ.शेचेव ने युद्ध की अवश्यम्भाविता और हिंसात्मक शान्ति की अनिवार्यता से इन्कार करते हुए विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया और मसदीय पद्धति से समाजवाद की स्थापना की बकासत की। ए.इ.शेचेव की ये मान्यताएँ चीनी नेताओं के गले नहीं उतरी। चीनी साम्यवादी दल ने ए.इ.शेचेव पर सशोधनवादी होने का आरोप लगाया और प्रालोचना-प्रत्यालोचना की खुली शुरुआत हुई। 1956 में और तत्पश्चात् 1961 में रूसी साम्यवादी दल की कांग्रेस में ए.इ.शेचेव द्वारा स्टालिन की निन्दा ने दोनों देशों में मतभेद और सैद्धान्तिक संघर्ष उग्र कर दिए। ए.इ.शेचेव के स्टालिन विरोधी अभियान को विस्तारितनीकरण की सजा दी गई। जब मास्को यूगोस्लाविया को साम्यवादी भ्रातृत्व में वापस बुलाने की तत्पर हुआ तो भी चीन को बड़ा बुरा लगा। सितम्बर, 1959 में ए.इ.शेचेव की अमेरिका-यात्रा चीन को पसन्द नहीं आई और इसलिए चीन की यात्रा के समय सोवियत नेता का कोई विशेष स्वागत नहीं किया गया। 1959 में अपनी चीन-यात्रा के समय ए.इ.शेचेव ने पुनः यह बात दोहराई कि साम्यवादी चाहे कितने ही सशक्त हो जाएँ, उन्हें पूँजीवादी जगत् के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने से बचे रहना चाहिए। चीनी मार्क्सवादीशे को ए.इ.शेचेव का उपदेश 'प्रतिस्पर्धावादी शक्तियों की प्रगतिशील शक्तियों पर विजय' जँसा लगा। 1959-60 में भारत-चीन सीमा-विवाद पर ए.इ.शेचेव की यह टिप्पणी भी चीनी नेताओं को अखरी कि दोनों देश अपना सीमा-विवाद शीघ्र ही शान्तिपूर्ण ढंग से निपटा ले।

दोनों देशों के बीच सैद्धान्तिक मतभेद तीव्र होते गए। जून, 1960 में बुखारेस्ट में रूमानिया-कर्मचारी-दल के तृतीय सम्मेलन में ए.इ.शेचेव ने पुनः कहा कि लेनिन का 'पूँजीवाद के विरुद्ध युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धान्त' अब लागू नहीं होता। दूसरी ओर चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ने घोषणा की कि जब तक साम्राज्यवाद विद्यमान है, युद्धों का सतरा बना रहेगा। जुलाई, 1960 से रूस द्वारा चीन की विकास-योजनाओं में कार्यरत सोवियत वैज्ञानिकों को वापस बुला लिया गया। चीन की सामग्री, मशीनें आदि भेजना भी बन्द अथवा सीमित कर दिया गया। 1961 में प्रकाशित सोवियत साम्यवादी दल के कार्यक्रम के माध्यम में 20 वर्ष की अवधि में रूस में साम्यवाद की स्थापना का नारा बुलन्द किया गया। इस कार्यक्रम में साम्यवाद का अर्थ वस्तुओं की प्रचुरता बनलाया गया। चीनी साम्यवादी दल को साम्यवाद की यह व्याख्या अत्यन्त आपूर्ति लगी। 1962 में

रूस द्वारा भारत को भिग विमान देने और उन्हें बनाने के कारखानों में सहायता देने का समझौता चीनी नेताओं को घातक प्रतीत हुआ। 1962 में ही क्यूबा काण्ड के सम्बन्ध में चीनी नेताओं ने कहा कि रूस का पहला दोष 'डुस्साहस' का था और दूसरा दोष 'बागजी शेर' अमेरिका के आगे 'घृणित आत्म-समर्पण' करने का। 1962 में ही भारत पर चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में अपनाई गई रूसी नीति ने भी चीन को नाराज करने में आग में घी का काम किया।

जुलाई, 1963 में मास्को में रूसी और चीनी साम्यवादी दलों की वार्ता न केवल असफल हुई बल्कि दोनों देशों ने एक-दूसरे की कटु आलोचना की। रूस ने पश्चिम के साथ सह-अस्तित्व के विचार का पोषण किया जबकि चीन ने कहा कि साम्राज्यवाद के पूर्ण विनाश के लिए युद्ध अत्यावश्यक है और तृतीय महायुद्ध अमेरिका तथा रूस को ही समाप्त करेगा, चीन को नहीं। 25 जुलाई, 1963 को महाशक्तियों में हुई अणु-परीक्षण-निरोध-सन्धि का चीन ने बहिष्कार किया। रूस पर आरोप लगाया गया कि वह अमेरिका के साथ मिलकर आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में अपना एकाधिकार कायम रखना चाहता है।

अक्टूबर, 1964 में क्लूश्चेव के हटने पर पीकिंग में खुशियाँ मनाई गईं, लेकिन जब रूस के नए नेतृत्व ने भी पश्चिमी जगत् के साथ सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास प्रकट किया तो चीनियों को बड़ी निराशा हुई। रूसी बोलशेविक प्रान्ति के 47वें वार्षिक उत्सव में चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई की कूटनीतिक वार्ता भी असफल रही क्योंकि रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन की एकात्मता के प्रान्तिकारी प्रयासों में चीन का साथ देने से इन्कार करते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में आस्था प्रकट की।

मैकान्तिक संघर्ष के अतिरिक्त दोनों देशों के बीच सीमा-विवाद भी उभरे जिन्होंने मजस्य सीमा-संघर्षों का रूप ले लिया। मार्च, 1969 में पूर्वी एशिया में उमूरी नदी के टापू दमिश्क के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में सैनिक मुठभेड़ें हुईं। रूस और चीन की वर्तमान सीमाओं का निश्चय रूस के जारों और चीन के मुचूँ सम्राटों के बीच हुई सन्धि द्वारा हुआ था। ये सन्धियाँ 1858 और 1860 में की गई थी, जिनके अन्तर्गत चीन ने लगभग 5 लाख वर्गमील क्षेत्रफल रूस को सौंपा था। चीन ने आरोप लगाया कि उस समय चीनी निर्बलता का लाभ उठाकर रूस ने ये सन्धियाँ लाद दी थी। रूस का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और रूसी भूमि ही रूस ने प्राप्त की थी। चीन और रूस में झगड़े का असली कारण वस्तुतः मंगोलिया रहा है। चीन अपनी बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए मंगोलिया पर दौन गढ़ाए हुए है जो चीन की गरह पर है तथा बहुत कम बसा हुआ है। मंगोलिया का पूर्वी भाग चीन के पास है और चीनी नेता चाहते हैं कि दोनों मंगोलिया मयुक्त होकर चीन का एक प्रदेश बन जाए। रूस इसे मानने को तैयार नहीं है। पीकिंग ने मंगोलिया पर अपना दावा पहले पहल 1964 में किया था कि रूस ने रूस 'स्वतन्त्र राज्य' को हटप दिया है, लेकिन रूसी चीनी दावे का ठुकराने रहे हैं।

विवाद तब पराकाष्ठा पर पहुँच गया जब 1965 में पहली बार यह चीनी आरोप पूरी तरह स्पष्ट किया गया कि प्रथम साम्यवादी क्रान्ति का जन्मस्थल नोर्विच संघ पूंजीवाद के पुनरुद्धार में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति-संयुक्तगण्य अमेरिका के साथ मिश्रता के लिए लानायित है। एक ऐसे राज्य के विरुद्ध जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद में विश्वास करता था, सम्भवतः इससे अधिक गम्भीर आरोप नहीं लगाया जा सकता था। इस समय तक स्थिति यह हो गई थी कि दोनों देश सुलभसुल्ला एक-दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को विफल करने वाली विदेश-नीतियों का अनुसरण करने लगे थे। दोनों ही देश इस बात के लिए भी प्रयत्नशील थे कि उन्हें साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत अधिकाधिक समर्थन मिले।

रूस और चीन के मध्य मतभेदों की खाई निरन्तर गहरी और चौड़ी होती जा रही है। फरवरी, 1979 में विपत्तनाम पर चीन का प्राक्रमण यदि सम्भा चलता तो इस बात की पूरी आशंका थी कि चीन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में रूसी सैनिक भी विपत्तनामी सैनिकों के साथ बन्धे से कन्धा भिड़ा कर लड़ते।

रूस-चीन विवाद के मुख्य कारण

1. दोनों देशों के बीच सैद्धांतिक मतभेद हैं। स्टालिनोत्तर युग की सोवियत नीति विश्व-क्रान्ति और युद्ध की प्रतिवायेंता में विश्वास नहीं करती, जबकि ताल चीन क्रान्ति, हिंसा और युद्ध द्वारा पूंजीवादो जगत के विनाश में विश्वास करता है। रूसी सरकार के सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय 'इन्टरनेशनल अफेयर्स' के दिसम्बर, 1971 के अंक में एक प्रकाशित लेख में रूसी लेखक जी. एगलिन ने लिखा था कि—“माओ की विदेश नीति लड़ाकू, खतरनाक तथा रक्तस्त्रजित है जिससे चीनी लोकतन्त्र को भारी हानि हुई है यह न तो मार्क्सवादी है और न ही लेनिनवादी।”

2. नेतृत्व का नशा दोनों ही देशों पर छाया हुआ है। रूस द्वारा साम्यवादी जगत् का एकछत्र नेतृत्व सहन करने को चीन तैयार नहीं है। एशिया में रूस के प्रभाव-विस्तार को चीन सन्देह की दृष्टि से देखता है।

3. भूमध्यसागर रूस और चीन के तनाव का एक केन्द्र है। रूस और अमेरिका के जहाज तो भूमध्यसागर में घूमते ही हैं, चीन की पनडुब्बियों ने भी इस सागर में घूमना आरम्भ कर दिया है। भूमध्यसागर में चीन की कुछ सैनिक और राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं। चीन चाहता है कि—(i) भूमध्यसागरीय देशों पर उसकी बात का वजन रहे, (ii) रूसी मसूवों को हर क्षेत्र में चुनौती दी जाए या उसके मार्ग में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न की जाए, (iii) अल्बानिया जैसे साम्यवादी देशों को चीन ने अपने प्रभाव में ले लिया है उन पर और रोब आतंकित रखा जाए, (iv) प्रग्रेसरों से सज्जित जिन पनडुब्बियों का विकास चीन कर रहा है उनकी सैनिक गतिविधियों का क्षेत्र पहले से ही तैयार कर लिया जाए ताकि रूस और अमेरिका के मुख्य क्षेत्र चीन की मार में आ सकें।

4. चीन का 1969 से पहले तब का नारा था विश्व के दो भाग हैं—
नमामाजवादी और असमामाजवादी। लेकिन सन् 1969 में चीनी साम्यवादी दल ने जो
नाम्यवादी व्याख्या की उसने सोवियत रुस को भी असमामाजवादी अथवा साम्राज्यवादी
राष्ट्रो की श्रेणी में ला दिया।

5. एक परमाणु शक्ति के रूप में चीन के विकास को न केवल रुस बल्कि
अन्य देश भी एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। प्रारम्भ में सोवियत सघ ने चीन
को परमाणुविक जानकारी दी, लेकिन ज्यो-ज्यो चीन के इरादे स्पष्ट होते गए। रुस
ने इस सम्बन्ध में प्राधुनिकतम प्रविधि के बारे में गोपनीयता बरती। 1959 में
1957 के उस समझौते को भंग कर दिया गया जिसमें रुस द्वारा चीन को परमाणु
रसम की प्रविधा का ज्ञान कराने का प्रावधान था परमाणु अस्त्रों के प्रश्न पर चीन
और रुस के मतभेद बढ़ते ही गए।

6. विवाद की एक बड़ी जड़ मंगोलिया है। चीन अपनी बढ़ती हुई आवादी
को बसाने के लिए प्रादेशिक विस्तारवाद के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। इसी
मंगोलिया पर, जिसे 'स्वतन्त्र मंगोलिया प्रजातन्त्र' कहते हैं, चीन की आँख है।
मंगोलिया का पूर्वी भाग चीन के अधिकार में है। चीन चाहता है कि दोनों मंगोलिया
एक होकर चीन का प्रदेश बन जाएँ। चीन का आरोप है कि रुस ने 'स्वतन्त्र
मंगोलिया' को हड़प लिया है। मंगोलिया के कारण दोनों देशों की सीमाओं पर
भारी सैनिक जमाव रहता है और कितनी ही बार सैनिक भड़पें भी हो चुकी हैं जिनमें
पराजित होकर चीनियों को पीछे हटना पड़ा।

7. अमेरिका भी रुस और चीन के मतभेदों को उकसाने के लिए उत्तरदायी
है। जब 1969 के बाद रुस-चीन सीमा पर भड़पें हुईं तो अमेरिकी समाचारपत्रों
में प्रचार किया गया कि सन् 1969 में रुसी सैनिक अधिकारी इस बात पर विचार
कर रहे थे कि चीन पर आक्रामक हमला किया जाए ताकि उसकी परमाणु शक्ति
समाप्त हो जाए। वास्तव में अमेरिका यह तो नहीं चाहता कि रुस और चीन के
बीच बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध हो क्योंकि इसका प्रभाव रुस और चीन के बाहर
दूर-दूर तक पड़ेगा। इसके अनिश्चित चीन की समाप्ति से रुस की शक्ति इतनी बड़
जाएगी। मगर अमेरिका यह अवश्य चाहता है कि दोनों देशों के बीच इस प्रकार का
तनाव बना रहे जिनमें अमेरिका लाभान्वित हो।

8. चीन दुनिया के हर देश में रुस विरोधी प्रचार कर रहा है। यूरोपीय
कम्युनिस्ट देशों में उसने रुस के प्रति घाग भड़काने की हर सम्भव चेष्टा की है।
अल्बानिया को रुस से विमुख करने में चीन को सफलता भी प्राप्त हुई है। रुसी
नेतृत्व चीन की इन कार्यवाहियों से परेशान है और अपने प्रभुत्व की रक्षा के
लिए व्यग्र है।

9. चीन को विश्वास होने लगा है कि पूर्वी एशिया में अमेरिका की सैनिक
उपस्थिति अस्वाची है जबकि जापान निरन्तर शक्तिशाली होकर पूर्वी एशिया में
गंभीरी रूप में छा जाने को प्रयत्नशील है, अतः अमेरिका को गन्तुलत बाधन रक्खकर

पूर्वी एशिया में सोवियत संध की उपस्थिति को असम्भव बनाकर, चीन की सैनिक उपस्थिति की सम्भावनाओं को सुदृढ़ कर सकता है। चीन और अमेरिका दोनों इस बात से सहमत हैं कि दक्षिण-पूर्वी एशिया से अमेरिका के हटने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति सोवियत संध द्वारा नहीं होनी चाहिए।

10. पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के सम्बन्धों में सुधार रूस को अभीष्ट है, लेकिन वह चीन और अमेरिकी सम्बन्धों में सुधार को पसन्द नहीं करता।

11. इस का विचार है कि युद्ध अवस्थामावी नहीं है और विश्वसक अस्त्रों के निर्माण के कारण यह वांछनीय भी नहीं है जबकि चीन का मत है कि समाजवाद की तथाकथित सैनिक सर्वोच्चता के कारण सशस्त्र-नीति व्यावहारिक है। चीनी नेतृत्व का यह विश्वास था कि साम्राज्यवादियों को भुलाने के लिए विवश किया जा सकता है और यदि ऐसा न हो तो युद्ध द्वारा उनके भ्रम्य का निर्णय किया जाना चाहिए चाहे उसमें एक निहाई या आधी मानव-सम्यता ही नष्ट क्यों न हो जाए। सितम्बर, 1976 में माओ की मृत्यु के बाद भी चीन के दृष्टिकोण में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है तथापि ऐसा आभास अवश्य होने लगा है कि नया नेतृत्व संधों की बजाय सहयोग की राजनीति पर चलने का प्रयत्न करेगा।

12. रूसियों का अपने समाज के सम्बन्ध में तर्क है कि वर्ग-संघर्ष की विजय पूर्ण हो चुकी है और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को सम्पूर्ण जनता के राज्य का रूप दे दिया गया है। चीनी इसको मात्र कुनक कहकर अस्वीकार करते हैं। उनके विचार से यह सोवियत संघ के अन्तर्गत प्रचुरता से बड़े नौकरशाही तत्वों पर आचरण डालने की एक योजना है जो सर्वहारा तानाशाही एवं वर्ग-संघर्ष सम्बन्धी लेनिनवादी विचारधारा के लिए छतरा है।

13. चीनी सोवियत संघ में प्राप्त आर्थिक सहायता से कभी भी सन्तुष्ट नहीं रहे। सोवियत युद्ध के लिए प्राप्त ऋण के दायित्व ने उन्हें और भी अप्रसन्न कर दिया। जब रूस ने चीन की सहायता बन्द कर दी तो चीन ने इसका अर्थ यह लगाया कि रूस उस पर साम्यवादी दल से वार्ता के लिए अधिक दबाव डालना चाहता है। रूसी नेतृत्व को यह विश्वास हो गया कि चीन को आर्थिक सहायता देने का वही अर्वाचनीय परिणाम होगा जो सैनिक सहायता का हुआ है।

14. अल्बानिया का प्रश्न विदेश नीति का विषय होते हुए भी दल का प्रश्न बन गया। प्रश्न था कि क्या सोवियत साम्यवादी दल को यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सा शासक दल साम्यवादी गुट में है और वास्तविक समाजवादी देश कौन सा है? सोवियत साम्यवादी दल ने अल्बानिया को एकपक्षीय कार्यवाही द्वारा गुट से निवास दिया क्योंकि उसने मास्को की प्रवृत्ति की थी। चीनियों ने रूस की इस कार्यवाही की अल्लोना की और अल्बानिया चीनी गुट में शामिल हो गया।

15. सोवियत संध के विरुद्ध चीन के अविश्वास का एक बड़ा ऐतिहासिक आधार भी है। राजनीतिक विचारकों और इतिहासकारों का तर्क है कि अभी तक

इतिहास में चीन की ओर से सोवियत संघ पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ जबकि इनके विनयीत आन्ति के पूर्व रूसी शासकों ने चीन पर कई बार आक्रमण करके उसके दू-भाग को हडन लिया था। वास्तव में सोवियत संघ भूततः यूरोपीय देश है और एशिया में उसका इतना विस्तार आन्ति के पूर्व रूसी शासकों की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का ही फल है।

इस प्रकार सोवियत-चीन वैमनस्य साधारण और तथ्यपूर्ण है। सीमा पर दोनों ओर सैनिक जमाव है और जब तक झड़पें हो जाती हैं। शिगत कुछ वर्षों से चीनी नेता आरोप लगाते आ रहे हैं कि सोवियत संघ ने उनकी सीमा पर भारी सैनिक जमाव कर रखा है जिससे चीन की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता की कसौटी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए चीन तेजी से सामरिक तैयारियाँ कर रहा है। पर यह कहना कठिन है कि सोवियत रूस की ओर से यह तय्यकधिन खतरा वास्तविक है या काल्पनिक। हाल के ही वर्षों का इतिहास चीनी विस्तारवादी मनोवृत्ति की पुष्टि करता है। चीन ने जिस प्रकार मित्र देश भारत की भूमि हड़पी है, पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत रूप से दी गई कश्मीर की भूमि को हड़पा है एवं मित्र देशों के साथ घोर विवादों का विषय बना है, उसे देखते हुए चीन के पक्ष में कुछ कहना वस्तुतः कठिन है। जो भी हो, सोवियत चीन संपर्क मात्र राजनीतिक और राजनयिक पर्यवेक्षणों के लिए विचारणीय विषय बना हुआ है। जहाँ तक सीमा पर सैनिक जमाव का प्रश्न है, यह एक स्थायित तथ्य है। सोवियत संघ के अनुसार चीन-सोवियत सीमा पर नियमित चीनी सेना बनी हुई। चीन के वहाँ प्रभेदास्त्र, तोपें और राइफल्स हैं जिनके मुँह उत्तरी पड़ोसियों की ओर हैं। सोवियत संघ की सीमा के साथ लगने वाले किर्गिज़ पर परमाणु प्रशिक्षण चीन करता रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी सीमा पर 3,65,000 सोवियत सैनिक 4,000 टैंक तथा 1830 विमान हैं जबकि सोवियत सीमा पर 16,25,000 चीनी सैनिक, 5,000 टैंक तथा 2,600 विमान संनात हैं। सोवियत संघ का यह भी आरोप है कि चीन पूँजीपति देशों जैसे अमेरिका, जापान और पश्चिमी यूरोप के देशों से बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद कर रहा है और तो और चीन के दक्षिण अफ्रीका और लानीनी अमेरिका के कुछ देशों से भी सम्बन्ध है। चीन के सोवियत सीमा पर पश्चिमी जर्मनी के कुछ देशों से भी सम्बन्ध है। चीन-सोवियत सीमा पर पश्चिमी जर्मनी के कुछ टैंक भी देने गये हैं।

चीन और सोवियत मर में सीमा सम्बन्धी दर्जनों लिखित और अलिखित सन्धियों और समझौतों हैं। ये सन्धियाँ और समझौते 1889 और 1915 के बीच हुए थे। इन सन्धियों और समझौतों का समय-समय पर जायजा भी लिया जाना रहा है लेकिन चीनी अधिकारियों की मान्यता है कि बहुत सा इलाका अभी भी विवादाम्बद है। चीन के अनुसार उसके 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नर किसी न किसी पड़ोसी देश का अधिकार है। इसमें से 15 लाख वर्ग किलोमीटर सोवियत संघ के अधीन है। चीन के अनुसार जब तक इस विवादाम्बद क्षेत्र को सुलझा नहीं

लिया जाता तब तक किसी भी तरह की वार्ता या संवाद बेमनसब और प्रभावहीन साबित होंगे। चीन ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि सोवियत संघ सचमुच शान्ति चाहता है तो दो प्रमुख मुद्दों पर सहमति होनी चाहिए। सीमा पर यथास्थिति बनाये रखने पर सहमति और सशस्त्र सेनाओं को एक दूसरे से दूर रखने का आश्वासन, उसके बाद परस्पर वार्ता द्वारा विवाद को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। चीन ने यह भी मांग की कि सोवियत सेनाएँ मंगोलिया से भी हट जाएँ। 1960 की सोवियत चीन सीमा को ही वास्तविक सीमा माना जाए। इन्हीं दो प्रस्तावों को चीन अपने ठोस सुझाव बताता है।

कम्युनिस्ट खेमे में चीन लगभग अलग-थलग पड़ गया है। यूरोप में उसका एकमात्र साथी अल्बानिया भी उससे अलग हो गया है। इसलिए सोवियत संघ से बिगाड़ के बाद अल्बानिया ने उसे जो थोड़ा बहुत सहयोग और समर्थन मिलता था वह भी अब तकरार में बदल गया है। एशियाई देशों में भी वियतनाम पर उसका दबदबा नहीं है और कम्बोडिया वियतनाम के मुकाबले कमजोर है। यही कारण है कि उसका भुकाव पश्चिमी देशों की ओर अधिक होता जा रहा है और पश्चिमी प्रायधिकी की जानकारी प्राप्त करने के लिए चीनी इजीनियर और वैज्ञानिक इन देशों में भेजे जा रहे हैं। अब इस मसले ने और व्यापक रूप अस्तिधार कर लिया है। चीन में नेतृत्व परिवर्तन जरूर हुआ है लेकिन सोवियत संघ की मान्यता है कि अभी भी माओवाद का होना चीन पर हावी है और जब तक माओवाद का हावी रहेगा चीन सोवियत सम्बन्धों में अधिक सुधार की गुँजाइश नहीं है।

वस्तुतः रूस और चीन के बीच संघर्ष के मूल कारण उतने सैद्धान्तिक नहीं है जितने कि राजनीतिक और सामरिक। साम्यवादी जगत् का नेतृत्व कौन करे— यह भागड़े की मूल जड़ है।

रूस-चीन के समझौते-प्रयास

अपने नीव मतभेदों के बावजूद भी रूस और चीन दोनों ही समझते हैं कि वे एक दूसरे के शत्रु नहीं बने रह सकते, अन्यथा अमेरिका की 'बन्दर बांट' नीति मफन हो जाएगी। पश्चिमी जगत् विज्ञेय कर अमेरिका के निहित स्वार्थों और वास्तविक इरादों से दोनों ही देश प्रच्छेदित तरह परिचित हैं, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने-अपने वर्चस्व हेतु तथा शक्ति-सन्तुलन को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही अमेरिका की मंथी के आकांक्षी हैं। वस्तुस्थिति को समझ कर ही रूस और चीन राग-मगम पर अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत करते रहे हैं तथा 1970 से दोनों के बीच सैनिक संपर्क की सम्भावना बहुत-कुछ कम हुई है। 1970 की 13 जनवरी को दोनों देशों ने सीमा-समस्या के समर्थन के लिए आपस में जो वार्ता की उससे उनके बीच मतभेद कुछ कम हुए हैं। अक्टूबर, 1970 में हुई सोवियत-चीनी व्यापार-सन्धि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध-सुधार की दिशा में एक कदम था जिसके अनुसार सोवियत रूस ने चीन से अपने व्यापार में 1971-72 में 200 प्रतिशत वृद्धि कर देने का आश्वासन दिया था। सितम्बर, 1973 में दक्षिण

चाऊ-एन-लाई ने ये आरोप लगाए कि रूस चीन के साथ स्थिति सामान्य बनाना नहीं चाहता, चीन की सीमा पर उसकी दृष्टि है। रूस और अमेरिका को संसार की सम्पत्ति परस्पर बाँट लेने का कोई अधिकार नहीं है एवं वर्साय-सन्धि संगठन का स्वरूप आक्रामक है, तथापि यह वाक्-युद्ध पहले के समान कठोर रूप लिए हुए नहीं था। वाक्-युद्ध दोनों देशों के बीच अब भी चल रहा है, किन्तु पारस्परिक मतभेद दूर करने के लिए भी दोनों ही उत्सुक हैं। राजनीति की दुनिया में न कोई स्थायी मित्र हो सकते हैं और न कोई स्थायी शत्रु। भारत-रूस-मैत्री चीन को खटकती है जबकि वास्तविकता यह है कि भारत-रूस-मैत्री न तो चीन और भारत के और न रूस और चीन के सामान्यीकरण में बाधक है। चीन को यह बात बहुत बुरी तरह खटकती है कि रूस भारतीय क्षेत्र पर चीनी अधिकार का पक्ष नहीं लेना। 30 अक्टूबर, 1975 को सोवियत संघ के चीनी मामलों के विशेषज्ञ श्री एन. निसेतोव ने कहा था कि पेरिंग घोखाघड़ी का सहारा लेकर भारत पर अपने सीमा सम्बन्धी विचार थोपने का प्रयत्न कर रहा है। चीनी विस्तारवाद पर लिखे गए अपने लेख में उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत के 14 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर रखा है तथा अभी तक वहाँ जमा हुआ है। प्रेक्षकों के मतानुसार संघ ने उक्त लेख द्वारा पहली बार भारत के इस बंध दावे को स्वीकार किया कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है।

9 सितम्बर, 1976 को माओ-त्से-तुंग की मृत्यु के बाद चीन के नए नेतृत्व का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण कुछ उदार बनता जा रहा है और फलस्वरूप रूस-चीन विवाद में कटुता कुछ कम हुई है, यद्यपि विरोध बदस्तूर चालू है। समय-समय पर दोनों देशों के बीच समझौता वार्ताएँ भी चली हैं, तथापि अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। 24 जुलाई, 1981 को चीन ने अफगान सोवियत संघ की सीमा-मन्धि को अवैध घोषित किया था। वास्तव में लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर रूस-चीन मतभेद बरकरार हैं और निकट भविष्य में ऐसी कोई आशा नहीं दिखाई देती कि दोनों देशों का विवाद समाप्त हो सकेगा।



अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रभाव (U.N.O.'s IMPACT ON INTERNATIONAL POLITICS)

“संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वास का प्रतीक है—यह विश्वास कि शान्ति सम्भव है।.....यह आशा से अनुप्राणित कार्य करने का एक यन्त्र है तथा विश्व के अनेक कोनों में यह कल्याणकारी कार्यों के लिए एक ढाँचे का कार्य कर रहा है।”
—डॉग हेमरशोल्ड

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर को अन्तिम रूप से निश्चित करने के लिए सानफ्रांसिस्को (अमेरिका) में संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ जो 15 अप्रैल से 26 जून, 1945 तक चला। 26 जून को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। पोलैण्ड के प्रतिनिधि कारणवश उपस्थित नहीं हो सके, अतः हस्ताक्षरों से लिए स्थान छोड़ दिया गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ के कुल 21 प्रारम्भिक सदस्य बने जबकि, अप्रैल 1982 के प्रारम्भ में संघ की सदस्य संख्या 156 थी। 24 अक्टूबर, 1945 को संघ का चार्टर लागू हुआ और यही दिन विश्व में प्रतिवर्ष ‘संयुक्त राष्ट्र दिवस’ (The U N. Day) के रूप में मनाया जाता है। फरवरी 1946 को लन्दन के वेस्ट मिनस्टर हाल में संघ की प्रथम बैठक हुई और 15 फरवरी, 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन समाप्त हुआ। संघ का प्रधान कार्यालय पहले लेक-सक्सेस (अमेरिका) में स्थापित हुआ और तत्पश्चात् न्यूयॉर्क में बने विशाल भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रसंघ का स्वरूप

संयुक्त राष्ट्रसंघ का स्वरूप उसके चार्टर या संविधान से स्पष्ट है। चार्टर की प्रस्तावना के प्रारम्भ में सदस्य-राष्ट्रों के विश्व-शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी संकल्पों को प्रकट किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और विश्व-शान्ति व सुरक्षा को प्रभावित करने की दृष्टि से संघ के उद्देश्य अग्रलिखित हैं—

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा की स्थापना करना, शान्ति पर होने वाले आक्रमणों को रोकना और उनके विरुद्ध प्रभावशाली सामूहिक कार्यवाही करना, शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून भंग करने वाली चेष्टाओं को दबाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सुलझाना ।

2 जनता के आत्म-निर्णय तथा समान अधिकार के आधार पर राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना तथा सार्वभौम शान्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना ।

3 अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहित करना ।

4 उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में मामज्जस्य स्थापित करने हेतु केन्द्र के रूप में कार्य करना ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का आधार ऐसे सिद्धान्तों पर रखा गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सम्बन्ध को प्रभावित करने की भूमिका तैयार करते हैं । मंत्र के सदस्य राज्यों को इन सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना होता है—

(i) सभी राज्य प्रभुत्व-सम्पन्न हैं और समान हैं ।

(ii) सभी सदस्य चार्टर के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों व कर्तव्यों का, सद्भावना से पालन करेंगे ।

(iii) सभी सदस्य-राष्ट्र अपने विवादों का निपटारा शान्तिपूर्ण ढंग से इस प्रकार करेंगे कि शान्ति, सुरक्षा व न्याय के भंग होने का भय न रहे ।

(iv) सदस्य-राष्ट्र अपने सम्बन्धों में आक्रमण की धमकी देने या दूसरे राज्यों के प्रति बल प्रयोग करने से दूर रहेंगे ।

(v) सदस्य-राष्ट्र चार्टर के अनुसार की जाने वाली संधि की प्रत्येक कार्यवाही में सब प्रकार का सहयोग व सहायता देंगे और वे किसी ऐसे देश की मदद नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संधि शान्ति और सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही करने वाला हो ।

(vi) शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखने के लिए तब आवश्यक कार्यवाही करेगा । संधि यह भी देखेगा कि गैर-सदस्य राष्ट्र भी यथासम्भव ऐसे कार्य न करें जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए ।

(vii) विश्व शान्ति और सुरक्षा के अनिर्दिष्ट संधि किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों और सिद्धान्तों की रचना इस प्रकार की गई है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की भूमिका तैयार करते हैं और इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना, विभिन्न राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना और मानव कल्याण के कार्य करना उसका कर्तव्य निर्धारित हो जाना है । संधि का सदस्य बनने वाला प्रत्येक राष्ट्र इन उद्देश्यों और सिद्धान्तों में अपनी निष्ठा प्रकट

करता है। इस प्रकार वह यह स्वीकार करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के क्षेत्र में और इसी प्रकार के अन्य कार्यों में वह संयुक्त राष्ट्रसंघ का हस्तक्षेप स्वीकार करेगा तथा उसे प्रोत्साहन देगा। सदस्य-राष्ट्रों की यह स्वीकृति ही संयुक्त राष्ट्रसंघ को इस दृष्टि से सक्षम बनाती है कि वह शान्ति व सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सीमाओं में रहते हुए हस्तक्षेप कर सके।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्था एक नजर में
(United Nations System at a Glance)

संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्था में स्थायी अंग, विशिष्ट अभिकरण और कनिष्ठ परिषदें और कोष सम्मिलित हैं। एक नजर में इस विश्व संस्था की व्यवस्था निम्नानुसार है—

United Nations System		
<i>Permanent Organs</i>	<i>Specialised Agencies</i>	<i>Conferences and Funds</i>
1. General Assembly	1. World Health Organization	1. United Nations Conference on Trade and Development
2. Security Council	2. Food and Agricultural Organization	2. Children's Fund
3. Trusteeship Council	3. Intergovernmental Maritime Consultative Organization	3. United Nations Special Fund
4. Economic and Social Council	4. International Civil Aviation Organization	4. International Monetary Fund
5. Secretariat	5. Universal Postal Union	5. International Bank for Reconstruction and Development
6. International Court of Justice	6. International Telecommunications Union	
	7. World Meteorological Organization	
	8. International Labour Organization	
	9. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	
	10. International Atomic Energy Commission	

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से संघ के अंगों के अधिकार व कर्तव्य

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से संघ के अंगों के अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार हैं—

महासभा (General Assembly)

प्रबोधक कार्यों के सिलसिले में महासभा ने अपने प्रस्तावों द्वारा अनेक बार सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों को अपने निषेधाधिकार का प्रयोग समय से करने, महाशक्तियों द्वारा मुद्द-प्रचार-रोकने, मदस्य-राज्यों को शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की अवधारणा स्वीकार करने और सघर्षरत पक्षों को अपने विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग में समाधान करने को प्रेरित किया है।

सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर महासभा नए देशों को संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाती है तथा सुरक्षा-परिषद् के साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। अप्रैल 1982 तक महासभा की सदस्य संख्या 156 थी। चार्टर के अनुसार महासभा को अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने की शक्ति प्राप्त है। यह उन प्रयासों की खोज करती है जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा तथा विश्व के राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक सहयोग की स्थापना की जा सकती हो। महासभा शस्त्रों को सीमित करने और निःशस्त्रीकरण पर विचार करती है। विश्व में शान्ति स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कोई भी सम्भव कदम उठा सकती है। सभ के अन्य अंगों की शक्ति की सीमा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का मन्देह उत्पन्न होने पर उसका निर्णय महासभा द्वारा ही किया जाता है। सुरक्षा-परिषद् का यह कर्तव्य है कि वह अपनी वार्षिक तथा विशेष रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करे। महासभा उस पर विचार करती है। सभ का बजट भी इसी के द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यही इस बात का निर्णय करती है कि किस देश को संघ के व्यय का कितना भाग वहन करना चाहिए। इस तरह महासभा अनेक कार्य करती है इन कार्यों को करने समय सभा द्वारा वाद-विवाद किया जाता है, सिफारिशें की जाती हैं, ध्यान आकर्षित किया जाता है, सूचना दी जाती है और आगे अध्ययन करने की पहल की जाती है। जिन विषयों पर सुरक्षा-परिषद् विचार कर रही हो उन पर महासभा विचार तब कर सकती है जबकि सुरक्षा-परिषद् द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाए।

न्याय, समझौते की शर्तों और उनमें परिवर्तन व संशोधन के अनुमोदन सहित, युद्ध के लिए सैनिक इलाकों के न्याय-समझौतों के जिन नामों का संयुक्त राष्ट्रसंघ पर उत्तरदायित्व हो, उनकी महासभा पूरा करती है। इसे कुछ निर्वाचन सम्बन्धी कार्य भी करने होते हैं। महासभा सुरक्षा-परिषद् के परामर्श पर संघ के महासचिव की नियुक्ति करती है।

महत्व में वृद्धि के कारण—सुरक्षा-परिषद् की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माताओं का विचार था कि सुरक्षा-परिषद् संघ की प्रधान कार्यकारी शक्ति होगी और महासभा एक वाद-विवाद मंच (Debating Forum) के रूप में कार्य करेगी। इसीलिए जहाँ परिषद् की बाध्यकारी शक्ति प्रदान की गई, वहाँ महासभा को केवल सिफारिशें करने का ही अधिकार दिया गया लेकिन कालान्तर में विभिन्न व्यवस्थाओं, परिस्थितियों और व्यवहारों के फलस्वरूप महासभा का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। महासभा की महत्व-वृद्धि में निम्नलिखित कारणों का विशेष योग रहा है—

1. संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य हैं, अतः विश्व की समस्याओं पर विचार करने के लिए यह एक अच्छा सार्वजनिक मंच है।

2. विशेषाधिकार के अनुचित और अधिक प्रयोग के फलस्वरूप सुरक्षा-परिषद् की स्थिति पहले के समान अधिक लाभकारी नहीं रही है और मरुटकाल में सदस्य-राष्ट्र परिषद् पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। विश्व-जनमत को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए वे महासभा को अधिक उपयुक्त स्थान समझते हैं।

3. शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव पारित करने के बाद से महासभा के नैतिक स्तर में बहुत वृद्धि हुई है और वह विवादों के निपटारे, सामूहिक सुरक्षा तथा निःशस्त्रीकरण के विषय में अधिक सक्रिय रही है।

4. महासभा की आपात्कालीन सेना की नियुक्ति से उसके महत्व में अधिक और पर्याप्त वृद्धि हुई है।

5. सुरक्षा-परिषद् के साथ-साथ महामभा को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का जो अधिकार चार्टर के अन्तर्गत प्राप्त है, उसके समुचित प्रयोग ने भी महासभा के प्रभाव में वृद्धि की है।

6. महासभा का अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार इसे सच के अन्य अंगों से अधिक उच्च स्थिति प्रदान करता है।

वास्तव में 15 सदस्यों की सुरक्षा-परिषद् उन अर्थों में सम्पूर्ण विश्व का अन्तर्राष्ट्रीय मंच नहीं कही जा सकती। क्लार्क आइकबर्गर (Clark M. Eicheberger) के मतानुसार, 'महासभा मानव-जाति के संशोधन का एक रूप है जिसमें राष्ट्र कानून एवं संशोधनात्मक प्रक्रिया के ढाँचे के अन्तर्गत शान्तिपूर्ण परिवर्तन की विविध समस्याओं पर विचार करने के माध्यम दौड़ रहे हैं। सदस्य-राष्ट्र स्वतन्त्र रूप से अपनी शिकायतें, प्रस्ताव और सुझाव महासभा में प्रस्तुत करते हैं, इस तरह यह विश्व का उन्मुक्त अन्तःकरण (Open Conscience of the World) है। स्टार्क (Starke) का यह निष्कर्ष सही है कि 'महासभा ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।'¹

महासभा की स्थिति में सुधार के सुझाव—डॉ. रामसहा गौतम ने महासभा की स्थिति में सुधार के कुछ उपयोगी सुझाव दिए हैं। डॉ. गौतम का विचार है कि—

“चार्टर में सशोधन द्वारा महासभा को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए जिससे उसे विश्व-संस्था की संसद का स्तर प्राप्त हो सके, उसके निर्णय सम्मानित हों एवं उनका उचित ढंग से पालन किया जाय। महासभा के महत्त्व को सुरक्षा-परिषद् द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए। उचित तो यह है कि सुरक्षा-परिषद् को, जो संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी की तरह है, महासभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। महासभा में सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का उस देश की जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि उक्त राज्य की जनता की यथार्थ भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होना है जिसमें सदस्य-राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों को नियमित रूप से भाग लेना चाहिए ताकि महासभा के वाद-विवादों का स्तर ऊँचा हो सके। कुछ विचारकों का यह मत है कि महासभा में प्रतिनिधित्व की पद्धति में भी परिवर्तन होना चाहिए। सदस्य-राष्ट्रों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए सोवियत संघ, भारत, अमेरिका तथा साम्यवादी चीन आदि बड़े देशों को 30 सदस्य भेजने का अधिकार होना चाहिए एवं महासभा में उनके 30 मत भी होने चाहिए। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इण्डोनेशिया आदि मध्य श्रेणी के राष्ट्र 15 सदस्य भेजें एवं उनके 15 मत हों। इसी प्रकार छोटे देश जनसंख्या के आधार पर 5 या सात सदस्य भेज सकें। ऐसी व्यवस्था में महासभा के सभी निर्णय अधिकतम जनसंख्या के हितों के आधार पर होंगे। परन्तु इस व्यवस्था को अव्यावहारिक कहकर निरस्त कर दिया गया है क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र में निहित ‘समानता’ के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा। अभी महासभा के प्रत्येक सदस्य-राज्य को केवल एक मत देने का अधिकार है चाहे वह राष्ट्र भारत हो या भूटान।”

“उचित तो यह है कि महासभा को अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक शक्ति के निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जो समय के साथ विश्व की एकमात्र सैनिक शक्ति बन सके एवं तब तक सभी सदस्य-राज्य स्वयं की पूर्णतया निःशस्त्र कर लें। महासभा को अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक शक्ति की व्यवस्था एवं अविकसित राज्यों की प्रगति के लिए धन-संग्रह का अधिकार भी होना चाहिए, परन्तु इस तरह का विचार सम्भव प्रतीत नहीं होता क्योंकि बड़े राष्ट्र अपनी सैनिक क्षमता सम्पन्न करने के लिए तैयार नहीं होंगे एवं यदि सभी ऐसा अवसर भी पाया तो वे संयुक्त राष्ट्र को अपनी सङ्ग्रहणा बन्धी नहीं सोंपेंगे जिसमें विश्व-शान्ति की स्थापना के नाम पर संयुक्त राष्ट्र उन्हीं पर शक्ति का प्रयोग करने लगे। धन-संग्रह के सन्दर्भ में भी बड़ी शक्तियाँ सहयोग नहीं करेंगी। 1960 में वागो में शान्ति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पातृकालीन सेना का निर्माण किया था जिसमें व्यय होने वाली धनराशि में

सोवियत संघ सहयोग नहीं करना चाहता था जिसके कारण संयुक्तराष्ट्र के समक्ष अधिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोवियत संघ का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र की आपात्कालीन सेना के माध्यम से कांगो में साम्राज्यवादी शक्तियों के हितों की रक्षा की गई है। इसी तरह का आर्थिक संकट अमेरिका के दृष्टिकोण से भी उत्पन्न हो सकता था। 1971 में साम्यवादी चीन को संयुक्तराष्ट्र की सदस्यता प्रदान किए जाने के साथ ही ताइवान को अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध संयुक्तराष्ट्र की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। उक्त सन्दर्भ में अमेरिका अपनी अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक पराजय के लिए इतना अधिक प्रमानित हुआ कि राष्ट्रपति निकसन ने संयुक्तराष्ट्र को दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग में कटौती करने की धमकी दे दी। इस सन्दर्भ में यह भी आवश्यक है कि चार्टर में ऐसी व्यवस्था की जाए कि संयुक्तराष्ट्र को सभी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।¹

सुरक्षा-परिषद् (Security Council)

पामर एव परकिन्स ने सुरक्षा परिषद् को 'संयुक्त राष्ट्रसंघ की कुञ्जी' (Key organ of the U. N.) कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य दायित्व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाए रखना है और चूँकि यह कार्य प्रधानतः महाशक्तियों का है, अतः सुरक्षा-परिषद् में महाशक्तियों को स्थायी सदस्यता और विशेषाधिकार से विभूषित किया गया है। सुरक्षा-परिषद् की रचना संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यकारी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में की गई है तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखने का मुख्य दायित्व परिषद् पर ही ढाला गया है। परिषद् ने अनेक अवसरों पर इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है, तथापि कुल मिलाकर वह अपने निर्माताओं की आशाओं के अनुकूल प्रभावी होने में असमर्थ रही है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्था के किसी भी अंग अथवा अभिकरण ने विशेषाधिकार और कियान्वयन के बीच इतना अधिक अन्तर और विवाद उत्पन्न नहीं किया है जितना सुरक्षा-परिषद् ने।² लगभग सभी राजनीतिज्ञ और नेता यह स्वीकार करते हैं कि परिषद् आशाओं के अनुकूल सफल नहीं रही है। आखिर इस असफलता का कारण क्या है? परिषद् अपनी निर्धारित भूमिका के निर्वहन में क्षिणित क्यों रही है? इन प्रश्नों का आधारभूत उत्तर सम्भवतः यही है कि महाशक्तियों की आपसी फूट, उनके आन्तरिक शीत-युद्ध और विचार-धाराओं तथा क्षेत्रीय प्रश्नों पर उनकी टकराहट आदि ने सुरक्षा परिषद् को उतना प्रभावशाली अंग नहीं बनने दिया है जितना 1945 में आशा की गई थी। महायुद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्तियों, चरकियों, खुले सघर्ष, आरोप-प्रत्यारोप आदि ने जिन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भयों और निराशाओं को जन्म दिया है तथा विश्व के राजनीतिक पटल को जिस प्रकार क्लुपित किया है, उसे सुरक्षा-परिषद् के गौरव को ठेस लगना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। आंशिक रूप

1 रामनवा नीलम : संयुक्तराष्ट्र, पृष्ठ 447-49

2 *Piano and Riggs* : op. cit., p. 88,

से सुरक्षा-परिषद् की कार्य-प्रणाली और निर्णयकारी-प्रक्रिया भी इसकी शिथिलता के लिए उत्तरदायी है।

संगठन और कार्य-विधि—चाटेंर के पाँचवें अध्याय में अनुच्छेद 23 से 32 तक सुरक्षा-परिषद् के संगठन, कार्यों, अधिकारों, मतदान-पद्धति आदि का वर्णन है। चाटेंर की मूल व्यवस्था के अनुसार पहले सुरक्षा-परिषद् में केवल 11 सदस्य थे—5 स्थायी और 6 अस्थायी, किन्तु अगस्त, 1965 में संधि के चाटेंर का संशोधन किया गया और परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। परिषद् के निर्णयों के न्यूनतम आवश्यक मतों की संख्या भी बढ़ाकर 7 से 9 कर दी गई। सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य 5 देश हैं—चीन (कम्युनिस्ट), फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा संयुक्तराज्य अमेरिका। 10 (मूलतः 6) अस्थायी अवस्था निर्वाचित सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। चाटेंर के अनुच्छेद 23 में स्पष्ट उल्लेख है कि परिषद् के अस्थायी सदस्य दो वर्षों के लिए चुने जाएंगे और इस अवधि के समाप्त होने पर किसी सदस्य को तुरन्त पुनर्निर्वाचन के लिए खड़े होने का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि राष्ट्रसंघ की परिषद् में निर्वाचक सीटों (Elective Seats) पर अधिकांश चुनावों से मध्यवर्ती शक्तियों (Middle Powers) का ही नियन्त्रण रहा और लघु शक्तियों को परिषद् में प्रवेश से लगभग वंचित रहना पड़ा। वर्तमान विश्व-संस्था की महासभा द्वारा 1963 में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा-परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों में 5 एशियायी और अफ्रीकी राज्यों, 1 पूर्वी यूरोप से, 1 लेटिन अमेरिकी तथा 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों में से होने चाहिए। परिषद् में अस्थायी सदस्यों का वर्तमान निर्वाचन इस निर्णय के अनुकूल है।

परिषद् का संगठन इस प्रकार का है कि वह लगातार काम कर सके, इसलिए संधि-स्थान में परिषद् के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधि हर समय रहना आवश्यक है। परिषद् की बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं और इसमें कोई सदस्य राष्ट्र चाहे तो उसका प्रतिनिधित्व उसकी सरकार का सदस्य या विशेष रूप से मनोनीत कोई दूसरा प्रतिनिधि कर सकता है। कार्यविधि के नियमों के अन्तर्गत परिषद् की बैठकों के बीच 14 दिन से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। परिषद् संधि-स्थान के अलावा किसी दूसरी ऐसी जगह भी, जहाँ वह काम करने में सुगमता समझे, अपनी बैठकें कर सकती है। परिषद् को इन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ज्योंही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को खतरा पैदा हो, अविलम्ब उसकी बैठक हो सके। पूर्ववर्ती राष्ट्रसंघ में ऐसी व्यवस्था नहीं थी।

परिषद् अपने कार्यों में सहायता के लिए सहायक समितियों की स्थापना कर सकती है। परिषद् की दो स्थायी समितियाँ (Standing Committees) हैं—(क) विशेषज्ञ समिति जो कार्यविधि की नियमावली का काम देखती है एवं (ख) प्रवेश समिति जो नवीन सदस्यों के प्रवेश का काम देखती है। इनके प्रतिरिक्त परिषद् समय-समय पर तदर्थ समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति भी करती है।

अनुच्छेद 47 में व्यवस्था है कि सुरक्षा-परिषद् को प्रस्तावित प्रश्नों पर स्वतन्त्र परामर्श और सहायता के लिए सैनिक स्टाफ समिति (Military Staff Committee) की स्थापना की जाएगी—(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी परिषद् की सैनिक आवश्यकताएँ, (ख) उसके अधीन सेना का प्रयोग और उनकी कमान, (ग) शस्त्रों का नियन्त्रण एवं (घ) सम्भावित निःशस्त्रीकरण ।

यह प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ का कोई भी सदस्य, चाहे वह सुरक्षा परिषद् का सदस्य न हो, परिषद् के सामने प्रस्तुत किसी भी मामले की बहम में भाग ले सकता है बशर्ते कि परिषद् को यह विश्वास हो कि उस मामले से उस सदस्य के हितों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसे सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होता । परिषद् को अपनी बहसों में ऐसे राष्ट्र के भाग लेने के लिए, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य न हो, न्याय सम्मत नियम बनाने का अधिकार है ।

परिषद् के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को एक मत प्राप्त है । परिषद् के निर्णय दो प्रकार के होते हैं—कार्य-विधि सम्बन्धी (Procedure) तथा असाधारण या सारभूत (Substantive) ।¹ चार्टर में व्यवस्था है कि कार्य-विधि सम्बन्धी सभी निर्णय किन्ही 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों से लिए जाएंगे । स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में स्थायी और निर्वाचित सदस्यों को समान मतदान-शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन अन्य अथवा असाधारण (Substantive) मामलों पर निर्णय के लिए पक्ष में सभी स्थायी सदस्यों के मतों सहित 9 सदस्यों के मत आने चाहिए । किन्तु किसी भी सदस्य को चाहे वह स्थायी सदस्य हो अथवा अस्थायी, शान्तिपूर्वक मुनभाए जाने वाले ऐसे मामलों में मतदान का अधिकार नहीं होगा, जिसमें उसका अपना सम्बन्ध हो । असाधारण मामलों में मतदान-व्यवस्था से स्पष्ट है कि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी सदस्य अग्रहमति प्रकट करता है अथवा प्रस्ताव के विरोध में मतदान करता है तो वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं समझा जाता । ऐसे विरोधी मतदान को निषेधाधिकार (Veto-Power) कहते हैं । यदि कोई स्थायी सदस्य परिषद् की बैठक में अनुपस्थित हो अथवा अपना मत न दे तो वह निषेधाधिकार नहीं माना जाता । परिषद् की मतदान-व्यवस्था से निष्कर्ष निकलता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए स्थायी सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है और यही महाशक्तियों की सर्वममति का सिद्धान्त है । पर उल्लेखनीय है कि यदि परिषद् गम्भीर गतिरोध के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर पाती अथवा आक्रमण को रोकने के लिए निषेधाधिकार के कारण अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती तो महासभा दो-तिहाई बहुमत से अपनी सिफारिश कर परिषद् को कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है । इस व्यवस्था के सम्बन्ध में पिछले अध्याय में विस्तार से विचार किया जा चुका है ।

कार्य एवं शक्तियाँ—अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए सुरक्षा-परिषद् को व्यापक

शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और उसको व्यापक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। चार्टर के अनुच्छेद 24 में स्पष्ट उल्लिखित है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा-परिषद् की है और उसे ही यह देखना है कि संधि की ओर से प्रत्येक कार्यवाही जल्दी और प्रभावपूर्ण ढंग से होती है। अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत मयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे चार्टर के अनुसार सुरक्षा-परिषद् के फैसलों को मानेंगे और उन पर अमल करेंगे। सुरक्षा-परिषद् को जिन अधिकारों व शक्तियों से सम्पन्न बनाया गया है उनका उल्लेख चार्टर के 6, 7, 8, और 12वें अध्याय में किया गया है। इसके अनुसार शान्ति व सुरक्षा की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से परिषद् की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

1 यदि किसी विवाद से विश्व की शान्ति और सुरक्षा को खतरा हो, तो दोनों विवादी पक्ष उसको सबसे पहले बातचीत, पूछताछ, बीच-बचाव, मेल, न्याय-पूर्ण समझौते, प्रादेशिक सस्थाओं या व्यवस्थाओं द्वारा या अपनी पसन्द के अन्य शान्तिपूर्ण साधनों से सुलझाने का प्रयास करेंगे, और सुरक्षा-परिषद् यदि आवश्यक सम्भोगे तो विवादी पक्षों को अपने भगड़े ऐसे साधनों से निपटाने की माँग करेगी। (अनुच्छेद 33)

2 सुरक्षा-परिषद् किसी ऐसे विवाद अथवा स्थिति की जाँच-पड़ताल कर सकती है जो अन्तर्राष्ट्रीय संधि का रूप ले सकता हो अथवा जिससे कोई दूसरा विवाद उठ सकता हो। सुरक्षा-परिषद् इस बात का भी निश्चय करेगी कि ये भगड़े अथवा स्थिति जारी रहने पर विश्व-शान्ति और सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है अथवा नहीं। ऐसे भगड़े या इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा हो जाने पर सुरक्षा-परिषद् किसी भी समय उसके लिए उचित कार्यवाही करने या समाधान के अन्य उपायों की सिफारिश कर सकती है। (अनुच्छेद 34, 36)

3 ये सिफारिशें करते समय सुरक्षा-परिषद् को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सामान्य रूप से कानूनी भगड़ों को अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के विधान के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। (अनुच्छेद 36)

4. सुरक्षा-परिषद् ही इस बात का निर्णय करेगी कि कौनसी चेष्टाएँ शान्ति को खतरे में डालने वाली, शान्ति भंग करने वाली और आक्रमण की चेष्टाएँ समझी जा सकती हैं। वही सिफारिश करेगी और तय करेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखने अथवा फिर से स्थापित करने के लिए कौनसी कार्यवाही की जानी चाहिए। किसी स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए सुरक्षा-परिषद् अपनी सिफारिशें करने अथवा किसी कार्यवाही का निश्चय करने से पहले विवादी पक्षों से ऐसी अस्थायी कार्यवाहियाँ करने की माँग करेगी जिन्हें वह उचित या आवश्यक समझती हो। इन अस्थायी कार्यवाहियों से विवादी-पक्षों के अधिकारों, दावों या उनकी स्थिति का कोई अहित न होगा। यदि कोई पक्ष इन प्रकार की अस्थायी कार्यवाहियाँ नहीं करना है तो सुरक्षा-परिषद् इस पर भी विधिवत् ध्यान देगी।

(अनुच्छेद 39, 40)

5. सुरक्षा-परिषद् अपने फैसलों पर प्रमत्त कराने के लिए ऐसी कार्यवाहियाँ भी निश्चित कर सकती है जिनमें सशस्त्र सेना का प्रयोग न हो। वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों से इस प्रकार की कार्यवाही करने की माँग कर सकती है। इन कार्यवाहियों के अनुसार आर्थिक सम्बन्ध पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से समाप्त किए जा सकते हैं। समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो और यातायात के अन्यान्य साधनों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है अथवा राजनीतिक सम्बन्ध बिच्छेद किया जा सकता है।

(अनुच्छेद 41)

6. अनुच्छेद 31 में उल्लिखित उपर्युक्त कार्यवाहियाँ यदि सुरक्षा-परिषद् की दृष्टि में अपर्याप्त हों अथवा अपर्याप्त सिद्ध हो गई हों, तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखने या फिर से स्थापित करने के लिए वह जल, स्थल और वायु-सेनाओं की सहायता से आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। इस कार्यवाही में संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य-देशों की जल, थल, वायु-सेना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, घेरा डाल सकती है अथवा अन्य दूसरे प्रकार की कार्यवाहियाँ कर सकती है।

(अनुच्छेद 42)

7. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग देने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सब सदस्यों का यह कर्तव्य माना गया है कि वे सुरक्षा-परिषद् की माँग पर विशेष समझौते के अनुसार अपनी सशस्त्र सेनाएँ, सहायता और अन्य सुविधाएँ, जिनमें मार्ग अधिकार भी शामिल होंगे, मुहैया करेंगे। सेनाओं की सख्या, उनके प्रकार, उनकी तैयारी और स्थिति आदि के बारे में निश्चय समझौते या समझौतों से किए जाएँगे और इस प्रकार के समझौतों की बातचीत सुरक्षा-परिषद् और सदस्यों अथवा सुरक्षा-परिषद् तथा सदस्य-समूहों के बीच की जाएगी और इन पर प्रमत्त तभी किया जा सकेगा जब हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अपनी-अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा इनकी पुष्टि कर देंगे। चार्टर में यह भी उल्लेख है कि सदस्य सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय वायुसेना की टुकड़ियाँ जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएँगे ताकि संयुक्त राष्ट्रसंघ तुरन्त सैनिक कार्यवाही कर सके। इन सैनिक टुकड़ियों की संख्या और तैयारी आदि के बारे में निश्चय सुरक्षा-परिषद् अपनी 'सैनिक स्टॉफ समिति' की सहायता से करेगी। सैनिक स्टॉफ समिति की सहायता से ही सामूहिक कार्यवाही के लिए योजनाएँ बनाई जाएँगी।

(अनुच्छेद 43, 45)

8. अनुच्छेद 47 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा-परिषद् की निम्नलिखित प्रश्नों पर स्वयन्त्र सलाह और सहायता देने के लिए एक सैनिक समिति का निर्माण किया जाएगा—(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा-परिषद् की सैनिक आवश्यकताएँ, (ख) उसके अधीन सेनाओं का प्रयोग और उनकी कमान, (ग) शस्त्रों का नियन्त्रण, और (घ) सम्भावित निःशस्त्रीकरण। सैनिक स्टॉफ समिति में सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों के स्टॉफ अध्याक्ष का उनके प्रतिनिधि रहेंगे। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ का कोई तत्स्थ समिति का स्थायी प्रतिनिधि न हो और समिति के

दायित्वों को ठीक तरह पूरा करने में उस सदस्य का भाग लेना आवश्यक समझा जाता हो तो समिति उसको सहयोग के लिए आमन्त्रित करेगी। इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि सुरक्षा-परिपद के उपयोग के लिए जो सशस्त्र सेनाएँ दी जाएँगी, उनका युद्ध सम्बन्धी निर्देशन सैनिक स्टॉफ समिति के हाथ में रहेगा और यह समिति सुरक्षा-परिपद के अधीन रहेगी। सैनिक स्टॉफ समिति उपर्युक्त प्रादेशिक समस्याओं-से सलाह लेने के लिए प्रादेशिक उपसमितियों का निर्माण भी कर सकती है। सैनिक स्टॉफ समिति को यह अधिकार सुरक्षा-परिपद द्वारा प्रदान किया जाएगा।

9 जब सुरक्षा-परिपद किसी राष्ट्र के विरुद्ध रोकथाम की या अपने निर्यातों को अमल कराने की कुछ कार्यवाही कर रही हो उस समय यह हो सकता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के सामने कुछ विशेष आर्थिक समस्याएँ उठ खड़ी हो। अतः अनुच्छेद 50 में यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र को, चाहे वह मयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य हो या नहीं, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सुरक्षा-परिपद से सलाह लेने का अधिकार होगा।

10. यदि मयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य पर कोई मशस्त्र आक्रमण होता है तो वह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से आत्मरक्षा का अधिकारी है। अनुच्छेद 51 यह व्यवस्था देता है कि उस राष्ट्र पर उस समय तक कोई रोक नहीं होगी जब तक सुरक्षा-परिपद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए स्वयं कोई कार्यवाही न करे। आत्मरक्षा के लिए सदस्य जो भी कार्यवाही करेंगे उनकी सूचना तुरन्त सुरक्षा-परिपद को देगे। लेकिन इससे सुरक्षा-परिपद के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखने या फिर से स्थापित करने के लिए कभी भी जो कार्यवाही चाहे कर सकती है।

11. स्थानीय विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा-परिपद प्रादेशिक संगठनों और एजेंसियों का माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक संगठन या एजेंसियों अपने क्षेत्रों में शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में जो भी कदम उठाती हैं, उनकी सूचना उन्हें नियमित रूप से सुरक्षा-परिपद को देनी पड़ती है।

12. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में मयुक्त राष्ट्रसंघ ने जो दायित्व ग्रहण किये हैं, उन्हें निभाने का भार भी सुरक्षा-परिपद पर ही है। सरक्षित प्रदेशों को किसी भी राष्ट्र के सरक्षण में देते समय सरक्षण सम्बन्धी शर्तों भी सुरक्षा-परिपद द्वारा ही तय की जाती हैं। वही इन शर्तों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। यदि कुछ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हों जो मयुक्त राष्ट्रसंघ के अरक्षण में हों, तो इन क्षेत्रों की राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए सुरक्षा-परिपद आवश्यक कदम उठा सकती है।

सुरक्षा-परिपद द्वारा की गई कुछ वाध्यकारी (सैनिक) कार्यवाहियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से परिपद ने कतिपय अवसरों पर जो वाध्यकारी (सैनिक) कार्यवाहियाँ कीं, उनमें में कुछ का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा।

1. परिपद् को शान्ति-स्वापता के सम्बन्ध में सैनिक कार्यवाही करने का सर्वप्रथम अवसर कोरिया-संघर्ष में मिला। जून, 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया गया। संयुक्तराज्य अमेरिका ने सुरक्षा-परिपद् में कोरिया का प्रश्न रखा। परिपद् द्वारा आदेश दिया गया कि युद्ध अविलम्ब बन्द कर दिया जाए और उत्तरी कोरिया की फौजें 38° के उत्तर में वापस चली जाएँ। उत्तरी कोरिया द्वारा आदेश की अवहेलना करने पर संयुक्तराज्य अमेरिका ने सुरक्षा-परिपद् में उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। रूस की अनुपस्थिति ने परिपद् में यह प्रस्ताव पास हो गया। कुछ राज्यों ने संधि की अपनी सेनाएँ प्रदान की और संयुक्तराज्य अमेरिका इन सेनाओं के साथ दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए पहुँच गया। कोरिया का युद्ध उत्तरी कोरिया के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ का युद्ध कहा गया। आलोचकों का यह मन रहा है कि व्यवहारतः कोरिया में की गई कार्यवाही संयुक्त राष्ट्रसंघ के नाम पर विशेषतः अमेरिकी कार्यवाही थी। विजय-पराजय के झूले में झूलते हुए अन्ततोगत्वा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेताओं को सफलता मिली और पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद युद्ध विराम हो गया।

वास्तव में सुरक्षा-परिपद् की सैनिक कार्यवाही से कोरिया का युद्ध विश्व-युद्ध बनने से रक गया। रत्नाकर आइज़न बर्गर के अनुसार, "कोरिया के विवाद ने विश्व को यह आशा बँधा दी कि यदि बड़ी शक्ति के विरुद्ध नहीं तो कम से कम एक बड़ी शक्ति के अधीन राज्य (Setellite) के विरुद्ध तो निश्चय ही सामूहिक कार्यवाही की जा सकती है।" कोरिया की घटना ने विश्व-संस्था के संचालन की कुछ नवीन परम्पराओं का प्रतिपादन किया तथा अनेक महत्त्वपूर्ण परिणामों को जन्म दिया—

(i) चार्टर के अनुसार सैनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में सुरक्षा-परिपद् के निर्णय को सदस्य-राष्ट्रों के लिए मानना आवश्यक था, पर कोरियायी घटना ने इसे ऐच्छिक बना दिया अर्थात् विश्व-संस्था को सैनिक सहायता देना सदस्य-राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर रहा। सुरक्षा-परिपद् ने संघीय सैनिक कार्यवाही में सहायता करने की सदस्यों से मिफारिश की थी इसका स्पष्ट अर्थ था कि यह सदस्यों की इच्छा पर था कि वे संघ को सैनिक सहायता दें अथवा न दें। उदाहरणार्थ, भारत ने सेनाएँ न भेजकर केवल निमित्ता सहायता भेजी तथा और भी देशों ने संघीय सैनिक कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

(ii) यह स्पष्ट हो गया कि परिपद् में यदि एक या अधिक स्थायी सदस्य अनुपस्थित हैं अथवा मत नहीं दे रहे हैं तो उनकी अनुपस्थिति परिपद् की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकती और उनका नियेषाधिकार (Veto-Power) सामू नहीं होता। सोवियत रूस की अनुपस्थिति में सुरक्षा-परिपद् द्वारा लिए गए निर्णय ने बीटो के सम्बन्ध में निश्चय ही एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया।

(iii) यदि रूस ने सुरक्षा-परिपद् का बहिष्कार न किया होता तो वह इतनी शीघ्रतापूर्वक प्रभावशाली कार्यवाही करने में सफल न होती। इस कमी की ध्यान में

रखते हुए अमेरिका ने 1 नवम्बर, 1950 को महासभा में 'शान्ति के लिए एकता' का प्रस्ताव रखा जिसने महासभा को शान्ति-रक्षा के नवीन अधिकार देते हुए उसके गौरव को बढ़ाया।

(iv) यह सिद्ध हो गया कि सभ की सैनिक कार्यवाही की सफलता उसके सदस्यों के सक्रिय सहयोग तथा महाशक्तियों के उत्साह पर आधारित है।

2 कांगो (1960-64) में संयुक्त राष्ट्रसाधीय सेनाएँ बाध्यकारी कार्यवाही के रूप से नहीं बल्कि बेल्जियम की सेनाओं के लौट जाने के बाद भी इसलिए बनी रही कि कांगो का गृह-युद्ध विरव-शान्ति के लिए कहीं खतरा न बन जाए। सुरक्षा-परिषद् की इस कार्यवाही के संचालन, देर-भाल आदि का उत्तरदायित्व महासचिव पर पड़ा। वास्तव में सम्पूर्ण कार्यवाही चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार बाध्यकारी नहीं थी और न ही तरसम्बन्धी प्रक्रियात्मक औपचारिक एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का पालन ही किया गया था, फिर भी सन् 1962-63 में कांगो क्षेत्र के नियन्त्रण के लिए सघीय सैनिक टुकड़ी द्वारा की गई कार्यवाही विशेषतः बाध्यकारी कदम था। कांगो में सुरक्षा-परिषद् द्वारा जो कार्यवाही की गई वह चार्टर के अध्याय 7 के अनुसार थी अथवा नहीं, यह प्रश्न आज भी विवादास्पद है। जो भी हो, संघीय कार्यवाही ने कांगो को कोरिया बनने से बचा दिया। यदि संघीय सेनाएँ वहाँ नहीं होती तो कांगो साम्यवादियों एवं पश्चिमी शक्तियों के राशस्त्र संघर्ष का अखाड़ा बन गया होता।

3 रोडेशिया (1965-66) द्वारा ब्रिटेन से एकतरफा स्वतन्त्र होने के निश्चय से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कार्यवाही करते हुए सुरक्षा-परिषद् ने दिसम्बर, 1966 के अन्त में तीसरे प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्रसंघ के इतिहास में पहली बार प्रदेशात्मक अनुशास्तियों लागू की। रोडेशिया द्वारा एकतरफा स्वतन्त्रता की घोषणा को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा माना गया। आलोचकों के अनुसार रोडेशिया के मामले में भी कोरिया के समान ही चार्टर के अनुच्छेद 39-43 के अनुसार कार्य हुआ और साथ ही यह प्रवृत्ति भी स्पष्ट हो गई कि सुरक्षा-परिषद् के अधिकार-क्षेत्र को गैर-कानूनी ढंग से बढ़ाया जाने लगा है। रोडेशियायी मामले में सनाय कार्यवाही से यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि क्या विद्रोहियों के विरुद्ध अथवा किसी सब (Federation) की किसी इकाई द्वारा केन्द्र से संघर्ष होने पर भव को यह अधिकार है कि वह सुरक्षा-परिषद् से सहायता प्राप्त करे।

निषेधाधिकार की समस्या (Problem of Veto-Power)

जैसा कि कहा जा चुका है, चार्टर के अनुच्छेद 27 में सुरक्षा-परिषद् की मतदान-प्रणाली का वर्णन है जिसमें प्रसाधारण अथवा सारभूत (Substantive) मामलों में परिषद् के 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों में 5 स्थायी सदस्यों का मत शामिल होना आवश्यक है। इन 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी सदस्य अपनी समझमति प्रकट करे अथवा प्रस्ताव के विरोध में मतदान करे तो प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं सम्भवा जाता। चार्टर में परिषद् पर साधारण और प्रसाधारण कार्य-प्रणालियों

में अन्तर करने वाली कोई व्यवस्था नहीं दी है। अतः जब यह प्रश्न उठता है कि कोई साधारण या प्रक्रियात्मक (Procedural) मामला माना जाए अथवा असाधारण (Substantive), तब दोहरे निषेधाधिकार (Double Veto) का प्रयोग होता है, अर्थात् पहले तो निषेधात्मक मतदान द्वारा किसी प्रश्न को असाधारण विषय बनने में रोका जाता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव के दायित्वों (Obligations) के विरोध में मतदान होता है। जॉन तथा एडवर्ट ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सीमावर्ती मामलों में यह प्रारम्भिक प्रश्न उठता है कि क्या विषय साधारण (Procedural) है और क्या स्वतः ही यह निषेधाधिकार का विषय है। वास्तव में इसी नियमन निषेधाधिकार में बदल दिया है। पहले तो एक नकारात्मक वोट दिया जाता है जिसमें सुरक्षा-परिपद किसी विषय को साधारण न माने और उसके बाद दूसरे वोट द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग कर प्रस्ताव को विफल बना दिया जाता है।

सुरक्षा-परिपद में मतदान की प्रक्रिया के अध्ययन से स्पष्ट है कि परिपद के स्थायी सदस्यों में से कोई भी किसी भी प्रस्ताव के विरोध में मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। इसके केवल दो ही अपवाद हैं—प्रथम, प्रक्रिया सम्बन्धी मामले; एवं द्वितीय, वे मामले जिनमें विरोध में मत देने वाली महाशक्ति स्वयं एक पक्ष हो। आलोचकों का आरोप है कि निषेधाधिकार की व्यवस्था के कारण सुरक्षा-परिपद अपनी सामूहिक सुरक्षा के कार्य में असफल हो गई है। आर्नोल्ड फोस्टर के अनुसार, “निषेधाधिकार का भय सम्पूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है। ऐसी व्यवस्था के रक्त में ही पक्षपात है। यह उस कार के समान है जिसका स्टार्टर (Starter) किसी भी समय उसकी यन्त्र-व्यवस्था में गड़बड़ी कर उसके एजिन को ठप्प कर सकता है।”

पृष्ठभूमि—निषेधाधिकार उचित है या अनुचित—इस प्रश्न के विवेचन से पूर्व यह उचित होगा कि निषेध-व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर विचार कर लिया जाए। जिस समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर का निर्माण किया जा रहा था, उस समय निषेधाधिकार पर काफी विचार-विमर्श हुआ था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यूवेल्ट का विचार था कि यदि स्थायी शान्ति की खोज करनी है और संयुक्त राष्ट्र जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को सकल बगाना है तो यह कार्य महाशक्तियों के पूर्ण सहयोग से ही पूरा हो सकेगा। दूरदर्शी ह्यूवेल्ट ने यह अनुभव कर लिया था कि भविष्यतः संघ अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे महान् राष्ट्रों के लिए किसी भी ऐसे संगठन में भाग लेना सम्भव नहीं होगा जिसमें अन्य राष्ट्र केवल अपने बहुमत के बल पर महाशक्तियों को कोई कार्य करने के लिए बाध्य कर दें। इस प्रकार की स्थिति को रोकने का एकमात्र उपाय निषेधाधिकार था। यह स्पष्ट था कि महाशक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसका परिणाम स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की समाप्ति हो सकता था। इन्हीं सब बातों पर विचार करके संयुक्तराज्य अमेरिका ने यही उचित समझा कि वह निषेधाधिकार की व्यवस्था नहीं होगी तो वह संगठन का सदस्य नहीं

बनेगा। समुक्तराज्य अमेरिका का स्पष्ट मत था कि सुरक्षा-परिषद् ऐसे निर्णय कर सकती है जिनके अनुसार उसको अपनी सेनाओं का उपयोग करना पड़े, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे उपयोग अपनी इच्छा से करे न कि अन्य राष्ट्रों द्वारा बाध्य होकर। यदि समुक्तराज्य अमेरिका ऐसे किसी उपयोग से सहमत नहीं है तो उसे इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिए कि यह अपनी निषेध-शक्ति द्वारा उस उपयोग के प्रस्ताव को रद्द कर दे।

परन्तु निषेधाधिकार का प्रबल समर्थन करते हुए भी अमेरिका इस अधिकार सीमित रखना चाहता था। वह इस बात के पक्ष में था कि विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान और नवीन सदस्यों के संगठन में प्रवेश पर निषेधाधिकार की व्यवस्था न की जाए, लेकिन रूस इसके लिए सहमत नहीं था। वह निषेधाधिकार को असीमित रखना चाहता था। रूस को यह जानना था कि पश्चिमी शक्तियों ने विवशता के कारण ही जर्मनी के विरुद्ध उसके साथ सहयोग किया था, अन्यथा वास्तव में दोनों के बीच मौलिक सैद्धान्तिक मतभेद थे। रूस को आशंका थी कि यदि भविष्य में सुरक्षा-परिषद् में पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व होगा तो वे बहुमत के आधार पर स्वेच्छपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। अतः उमने अपने हितों की रक्षा के लिए निषेधाधिकार पर बल दिया और कहा कि या तो सुरक्षा-परिषद् के स्थाई सदस्यों को यह अधिकार दिया जाए अथवा समुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना ही न की जाए। अतः यही निश्चय हुआ कि निषेधाधिकार असीमित रूप से प्रदान किया जाए किन्तु इसका प्रयोग अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही हो।

निषेधाधिकार का प्रयोग—चार्टर के निर्माताओं का विचार था कि महा-शक्तियों का युद्धकालीन सहयोग विश्व-संस्था के मंच पर भी जारी रहेगा, लेकिन शीघ्र ही उनकी आशाओं पर तुलादापात हो गया। भयंकर शीतयुद्ध चालू हो गया और महाशक्तियों ने खुलकर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। एक अध्ययन के अनुसार सन् 1964 तक अकेला सोवियत रूस ही 103 बार निषेधाधिकार का उपयोग कर चुका था जबकि तुलनात्मक दृष्टि से ब्रिटेन, फ्रांस तथा राष्ट्रवादी चीन ने इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही कम किया है और समुक्तराज्य अमेरिका द्वारा अभी तक कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। सोवियत रूस का तर्क है कि सुरक्षा-परिषद् में पश्चिमी शक्तियों के बहुमत के मुकाबले अपने हितों की रक्षा करने का उसके पास एकमात्र उपाय निषेधाधिकार और विरोधी प्रस्तावों को रद्द करना ही है।

निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क

1. पाँच महान् राष्ट्रों को निषेधाधिकार प्रदान करके सभी सदस्यों को समानता का स्तर देने सम्बन्धी समुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है। निषेधाधिकार छोटे राष्ट्रों पर जबरदस्ती लादा गया है। महाशक्तियों के दबाव के कारण उन्हे समुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर को निषेधाधिकार के अनुच्छेद मंजूर स्वीकार करना पड़ा था।

2. निपेधाधिकार के कारण सुरक्षा-परिपद् शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था सम्बन्धी दायित्वों का समुचित रूप से पालन करने में असमर्थ हो गई है। यह अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान में सबसे अधिक बाधक है।

3. निपेधाधिकार पृष्ठपोषक राज्यों (Client States) को एक सुनी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है। यह सम्भव है कि प्रत्येक स्थायी सदस्य अपने मित्र राष्ट्रों को निपेधाधिकार सरक्षण प्रदान करे। इस प्रकार यह भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य स्थायी सदस्यों के नेतृत्व में अनेक गुटों में विभक्त हो जाएंगे। यह भय निराधार नहीं है क्योंकि अमेरिका और रूस के नेतृत्व में दो शक्तिशाली गुट पहले ही जन्म ले चुके हैं और तात् चीन को सच में प्रवेश और सुरक्षा-परिपद् में स्थायी सदस्यता प्राप्त होने से वह सम्भवतः अपने नेतृत्व में एक तीसरे गुट को खड़ा करने से बाज नहीं आएगा।

4. निपेधाधिकार के कारण सुरक्षा-परिपद् में जो गतिरोध उत्पन्न होते रहे हैं, उनसे राज्यों की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की आपत्ता दुरी तरह उभरना गई है।

5. निपेधाधिकार के दुरुपयोग के कारण कई स्वतन्त्र राष्ट्र अनेक वर्षों तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं बन पाए और प्राज भी कुछ राष्ट्रों का सच में प्रवेश भटका हुआ है।

आलोचकों का आरोप है कि निपेधाधिकार द्वारा महाशक्तियों को संयुक्त राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्राधिपत्य हो गया है। इस केस्सन के अनुसार महाशक्तियों का यह अधिकार अन्य सभी सदस्यों पर कानूनी प्रभुसत्ता स्थापित करता है, और उनके निरंकुश और स्वच्छन्द शासन का सूचक है। इसके कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ के वास्तविक और वांछनीय निर्णय नहीं हो पाते।

निपेधाधिकार के पक्ष में तर्क

निपेधाधिकार की आलोचनाओं में वजन है, तथापि कुछ व्यावहारिक तथ्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। निपेधाधिकार की व्यवस्था में जो खतरे निहित हैं उनसे कहीं अधिक भयावह खतरे इस व्यवस्था के न रहने में हैं। किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को सफलता सभी मिल सकती है, जब उसे विश्व की महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त हो और ये महाशक्तियाँ किसी भी ऐसी सस्या में भाग नहीं लेना चाहेंगी जिसमें अन्य देश केवल अपने बहुमत से उन्हें किसी कार्य करने अथवा न करने के लिए बाध्य करदे। इसे रोकने का एकमात्र उपाय निपेधाधिकार ही है। ए. ई. स्टीवेंस ने ठीक ही लिखा है कि "महत्त्व के नियम का जन्म अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं से होता है। ये 5 महान् राज्य किसी मामले पर राजी नहीं होते हैं तो उनमें से किसी के विशद शक्ति का प्रयोग बड़े युद्ध को जन्म देगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी सम्भावना से बचने के लिए हुई थी।"

निपेधाधिकार असहमति-सूचक संक्षण है न कि इसका कारण, अतः निपेधा-व्यवस्था के समाप्त कर देने से महाशक्तियों के मतभेद दूर नहीं होंगे और न ही इसमें कोई बड़ा लाभ होगा। यदि निपेधाधिकार की व्यवस्था न भी होती, तो भी सुरक्षा-परिपद् में गम्भीर खतरे उत्पन्न करने की दूसरी युक्तियाँ निकाल ली जाती और उनका

भी उतना ही दुरूपयोग किया जाता, जितना वर्तमान निपेधाधिकार व्यवस्था का किया जा रहा है। महाशक्तियों की प्रसहमति की उपेक्षा कर देने की व्यवस्था वा स्पष्ट परिणाम वही होगा जो राष्ट्रसंघ के साथ हो चुका है।

यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि निपेधाधिकार के प्रयोग के फलस्वरूप सुरक्षा-परिपद का काम ठप्प हो गया है। अब तक का अनुभव अधिकांशतः यही सिद्ध करता है कि निपेध-शक्ति का दान अधिक प्रयोग होने के कारण किसी अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में अधिक बाधा नहीं आई है। जिन निर्णयों के लेने में यह बाधक बना है, उनके न लेने पर भी विश्व-शान्ति को किसी प्रकार का खतरा नहीं पहुँचा है, बल्कि कई बार निपेधाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की शान्तिपूर्ण उपायों से सुलझाने में सहायक हुआ है। जब कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा-परिपद में ब्रिटेन व अमेरिका ने खुल कर पाकिस्तान का समर्थन किया और निर्लज्जतापूर्वक न्याय का गला घोट्टा, तब सोवियत रूस के निपेधाधिकार के प्रयोग ने स्थिति को संभालने में और न्याय की रक्षा करने में सहायता प्रदान की।

वास्तव में निपेधाधिकार संघ के विभिन्न पक्षों में सन्तुलन कायम रखने में सहायक सिद्ध हुआ है। यदि निपेध-व्यवस्था न होनी, तो संयुक्त राष्ट्रसंघ पूरी तरह एक गुट विशेष का शासन बन जाता जिसे अपनी मनमानी करने की पूरी छूट मिल जाती।

पुनश्च, निपेधाधिकार को अनेक स्वरूप परम्पराओं के विकास और व्यावहारिक कदमों ने पूर्वपेक्षा कुछ कम प्रभावशाली बना दिया है। शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव पास होने के बाद न तो यह अधिकार कोई नया अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष उत्पन्न करता है और न उसे धागे बढ़ाता है। इनके होते हुए भी महासभा द्वारा अनेक कार्य सम्पादित किए जाते हैं। शान्ति निरीक्षण आयोग, सामूहिक उपाय समिति, आदि की स्थापना द्वारा महासभा ने सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को निपेध के दुष्प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया है।

निष्कर्ष रूप में उपयोगी यह होगा कि नई सदस्यता और शान्तिपूर्ण समझौतों के सम्बन्ध में तो निपेधाधिकार आंशिक है, अतः समाप्त हो जाना चाहिए। परन्तु शान्ति मग और आक्रमण की स्थिति में सैनिक कार्यवाही के लिए इस अधिकार का प्रयोग कायम करना चाहिए, अन्यथा अनेक गम्भीर और नवीन समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। निपेधाधिकार के प्रयोग की समस्या को श्री गुडरिच एवं हैम्बरो ने ठीक प्रकार से आँका है। उन्होंने लिखा है—“राष्ट्रों में जो समझौता नहीं हो रहा है उसके कारण निपेधाधिकार का प्रयोग हो रहा है। उसके लिए जिसकी उत्तरदायी ठहराया जाए, वह निर्माय सेना कठिन है। वास्तव में यह एक राजनीतिक प्रश्न है। रूस ने इस अधिकार का अधिष्ठान प्रयोग किया है परन्तु उसका तर्क है कि विरोधी बहूमतों से बचने के लिए वह इस अधिकार का प्रयोग करता है। यह स्वीकार करना चाहिए कि महाशक्तियों की सर्वसम्मति और उनकी समान प्रभुता का ही यह अर्थ है कि उनमें मतभेद और बहु-सम्मति सम्भव है। स्थायी सदस्यों में जो आशा

से अधिक मतभेद रहे हैं, उनका मूल कारण उनकी नीतियों का मतभेद है जिसने भ्रान्ति-सन्धियों के मार्ग में रुकावट डाली है तथा क्षतिग्रस्त देशों में गुटोत्तर पुनर्विकास को रोक दिया है।"

सुरक्षा-परिपद की भावी भूमिका

यद्यपि सुरक्षा-परिपद ने कोरिया, वींगो, पश्चिमी इरियन, यमन, साइप्रस आदि में उत्पन्न खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने में अभिकाधिक रुचि और सक्षमता प्रकट की है और 1965 में भारत-पाक युद्ध को रोकने में तेजी से सफल कार्यवाही करने का श्रेय प्राप्त किया है, तथापि अनेक महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्नों पर उसकी नीति तथा कार्य-प्रणाली बहुगुणी, दुर्बुद्धी और क्षिणिल रही है। उदाहरण के लिए, कश्मीर विवाद में सुरक्षा-परिपद ने ध्याय का जिस प्रकार गला घोटा है, वह विश्व-शान्ति के गौरव को क्षीण करने वाला है। 1968 में चेकोस्लोवाकिया के सङ्घटन में सुरक्षा-परिपद की निष्क्रिय भूमिका विश्व-संस्था के भविष्य के लिए एक चेतावनी है। पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल (1971) में भीषण नरसंहार द्वारा एक करोड़ों के लगभग शरणार्थियों को भारत भूमि में भागने के लिए विवश करके ऐसी विकट स्थिति पैदा कर दी जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क अनिवार्य हो गया और विश्व-शान्ति को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया। सुरक्षा-परिपद, महासभा, महासचिव आदि सभी दम दिशा में कोई प्रभावशाली कार्यवाही करने में असमर्थ रहे। विश्व-संस्था का मूल दर्शक बने रहना और नत्तक की बात थी। ईराक-ईरान संघर्ष की सुलझाने में भी मार्च, 1982 तक सुरक्षा-परिपद कुछ नहीं कर सकी है।

निष्कर्ष यह है कि अनेक मामलों में प्रभावशाली भूमिका ग्रहण करते हुए भी सुरक्षा-परिपद का इतिहास कुल मिलाकर इसके निर्माताओं की आशा के विपरीत रहा है। परिपद महाशक्तियों के हाथों का खिलौना बन कर रह गई है। वास्तव में विश्व-संस्था और सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत् पर सुरक्षा-परिपद का भावी प्रभाव बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर रहेगा कि वह शान्ति और सुरक्षा के मामलों में प्रभावशाली कार्यवाही करने में कितनी समर्थ सिद्ध होती है। शीत-युद्ध, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वित्तीय प्रबन्ध, महासभा के बड़ते हुए क्षेत्र, परिपद की सदस्यता-विस्तार के पतस्वरूप बढ़ते हुए गठबन्धन और दबाव आदि अनेक ऐसे तत्व हैं जो परिपद की भावी भूमिका पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। यदि सुरक्षा-परिपद को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की स्थापना की दिशा में नियामक भाग लेते हुए देखना है तो यह बहुत कुछ महाशक्तियों के सहयोग पर निर्भर है। यदि परिपद के स्थायी सदस्य इसके गौरव को बनाए रखने में सहायक होंगे तभी परिपद का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। यह अनुपयुक्त नहीं होगा कि परिपद को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए नए समर्थों के प्रकाश में चाटें में कुछ अनुकूल सल्लोचन किए जाने चाहिए। शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में विभिन्न कार्य

करती है। यह अपने सहायक अंगों द्वारा मानव-जीवन के व्यापक क्षेत्रों का अध्ययन करती है और उस आधार पर व्यापक कार्यवाही करने की सिफारिशें करती है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिपद, महासभा के अधीन, संसार से गरीबी और हीनता को मिटाकर एक स्वस्थ एवं समुन्नत विश्व के निर्माण में प्रयत्नशील है। यदि विभिन्न राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में विवाद हो तो परिपद उन्हें मिटाने का प्रयत्न करती है और विश्व के चहुँमुखी विकास में सभी देशों के सहयोग पूर्ण दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन देती है।

पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास के लिए इस संस्था द्वारा आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता-योजनाओं की स्थापना की गई है। परिपद की प्राविधिक सहायता-समिति का मुख्य उद्देश्य ही दुःख और दरिद्रता से मानव-जाति को मुक्ति दिलाना है। यह अर्द्ध-विकसित देशों को विशेषज्ञ भेजती है और उन्हें मशीनों, यन्त्रों, उपकरणों आदि की पूर्ति के लिए आर्थिक सहयोग देती है। परिपद का मुख्य लक्ष्य मानव-अधिकारों को प्रोत्साहन देना है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए परिपद द्वारा विभिन्न आयोग स्थापित किए गए हैं। परिपद ने शरणार्थियों तथा राज्यहीन व्यक्तियों के लिए नियम बनाए हैं तथा ट्रेड यूनियनों के अधिकारों, दासता और बेगार का अध्ययन किया है। स्त्रियों की स्थिति पर, सूचना एवं व्यापारिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी आयोग स्थापित किए हैं तथा इन विषयों में विभिन्न समझौतों के प्रारूप तैयार किए हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिपद के कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, व्यापक और दूरगामी हैं जिन्हें सम्पन्न करने के लिए अनेक आयोगों, विशेषीकृत अभिकरणों तथा समितियों की स्थापना की गई है। परिपद में आयोगों के दो रूप हैं—कार्यात्मक और प्रादेशात्मक। प्रथम वर्ग में वित्तीय आयोग, जनसंख्या आयोग, सामाजिक आयोग, मानव-अधिकार सम्बन्धी आयोग, स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी आयोग आदि हैं। प्रादेशिक या क्षेत्रीय आयोगों में यूरोप के लिए आर्थिक आयोग, एशिया तथा गुड्रूपूर्व के लिए आर्थिक आयोग आदि उल्लेखनीय हैं। इन आयोगों के अलावा परिपद के अन्तर्गत अनेक विषय अभिकरणों (Specialised Agencies) की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए, साच एवं कृषि मण्डल, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मण्डल (ILO), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, विश्व-स्वास्थ्य-मण्डल आदि।

न्यास-परिपद (Trusteeship Council)

पहले राष्ट्रसंघ में संरक्षण-व्यवस्था (Mandate System) थी और अब बहुत-कुछ इसी प्रकार की न्यास व्यवस्था कायम की गई जिसका मुख्य मिशन यह है कि विश्व में अनेक पिछड़े हुए तथा अविक्सित प्रदेश हैं जिनका विकास तभी सम्भव है जब सम्य और उन्नत देश उन्हें सहयोग प्रदान करें। अतः उन्नत देशों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने आपको न्यासी (Trustee) समझकर अविगत प्रदेशों के हितों की देखभाल करते हुए उनके विकास में हर सम्भव सहयोग दें। राष्ट्रसंघ की संरक्षण-व्यवस्था केवल जर्मनी, टर्की आदि से पीड़ित प्रदेशों के लिए थी, न्यास पद्धति का ध्येय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाए गए सभी

क्षेत्रों तक विस्तृत है। न्यास पद्धति के मूल उद्देश्य हैं—(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की वृद्धि करना, (ख) न्यास-प्रदेशों का स्वशासन की दिशा में विकास करना, (ग) मानव-अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन देना तथा यह भाव जाग्रत करना कि ससार के सभी लोग अन्वोन्यायिक हैं, एवं (घ) सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक मामलों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समान व्यवहार का विश्वास दिलाना।

न्यास-पद्धति के अन्तर्गत समाविष्ट प्रदेश दो भागों में विभाजित हैं—अस्वशासित प्रदेश (Non-Self-Governing Territories), एवं न्यास या सुरक्षित प्रदेश (Trust Territories)। प्रथम प्रकार के प्रदेश (वे पराधीन प्रदेश तथा उपनिवेश जो सुरक्षित प्रदेश न बनाए गए हों) ब्रिटेन, फ्रांस आदि पश्चिमी देशों के साम्राज्य के अन्तर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के अर्थात् न्यास-प्रदेश वे हैं जो न्यास-समझौते के द्वारा, जो कि सम्बन्धित राज्यों के मध्य होते हैं और जिन पर महासभा की स्वीकृति अनिवार्य है, न्यास-प्रदेश बना दिए जाते हैं।

कुछ वर्षों के पूर्व न्यास-पद्धति के अन्तर्गत न्युगिनी, दम्राण्डाउरुण्डो फ्रेंच कैमरुन्स, फ्रेंच टोगोलैण्ड, पश्चिमी समोया, टांगानिका, ब्रिटिश कैमरुन्स, नौरु प्रशान्त महासागर द्वीप, सुमालीलैण्ड, टोगोलैण्ड नामक 11 देश थे। अब ये सभी स्वाधीनता प्राप्त कर चुके हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

(The International Court of Justice)

यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का न्यायिक अंग है। यह वही पुराना अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है—जिसे राष्ट्रसंघ ने सन् 1901 में हेग में स्थापित किया था। नवीन न्यायालय अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा कई प्रकार से दोष-मुक्त है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार तथा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार (Voluntary Jurisdiction) के अन्तर्गत न्यायालय अपनी सविधि (Statute) की धारा 36 के अनुसार उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको सम्बन्धित राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। केवल राज्य ही न्यायालय के विचारणीय पक्ष हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं।

अनिवार्य क्षेत्राधिकार (Obligatory Jurisdiction) को वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार (Optional Compulsory Jurisdiction) भी कहा जाता है जिसके अनुसार राज्य स्वयं की घोषणा द्वारा अर्थात् कि क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है—सन्धि की व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रीय कानून से सम्बन्धित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम। राज्य घोषणा करते समय कोई भी शर्त लगा सकता है। कभी-कभी तो ऐसी शर्तों के कारण यह घोषणा वास्तविक

न्यायद्वार में निरर्थक धन जाती है तथापि सशर्त होते हुए भी वैकल्पिक धारा अनिवार्य न्यायिक निर्णय की सर्वाधिक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। महासभा अथवा सुरक्षा-परिषद् किसी भी कानूनी प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श माँग सकती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप में प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना-पत्र में सम्बन्धित प्रश्न का विवरण तथा वे सभी दस्तावेज होते हैं जो उस प्रश्न पर प्रकाश डाल सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है और निद्धान्त रूप में सुरक्षा-परिषद्, महासभा या अन्य संस्था इसकी उपेक्षा कर सकती है, पर व्यवहार में ऐसा करना सर्वथा कठिन होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण विवादों के समाधान में महयोग दिया है। उदाहरण के लिए, मोरक्को का मामला, एंगो-ईरानी मामला, भारतीय प्रदेशों से पुर्तगाल को मार्ग देने के अधिकार का विवाद, कोरू-चेनल विवाद, एंगो-नामिबिया में मछलीगाह विवाद आदि को गिनाया जा सकता है। न्यायालय के कार्य-संचालन में विभिन्न देशों तथा गुटों ने बाधा डाली है। राज्यों की उपेक्षा तथा उनके अनहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण यह अधिक उपयोगी तथा शक्तिशाली संस्था नहीं बन सकी है।

सचिवालय और महासचिव

(The Secretariat and the Secretary General)

राष्ट्रसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अनुभव से लाभ उठाते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में एक सचिवालय की व्यवस्था की गई है जो अपनी संरचना में एकात्मक (Unitary) है। चार्टर के अनुच्छेद 67 में उल्लिखित है कि "सचिवालय में महासचिव और संघ की आवश्यकतानुसार कर्मचारी वर्ग रहेगा। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर महासभा करेगा। वहीं संघ का प्रमुख अभिमानक (प्रशासकीय अधिकारी) होगा।" अनुच्छेद 101 के अनुसार, महासचिव मंत्र के पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।

सचिवालय का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क तथा जेनेवा में है, किन्तु क्षेत्रीय मंत्रालयों, प्रादेशिक आयोगों तथा सूचना केन्द्रों के लिए इसके कर्मचारी विषय के कई भागों में बिखरे रहते हैं। सचिवालय द्वारा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। यह संघ के अंगों एवं अभिकरणों की मीटिंग के लिए अनेक प्रचार को मेवाएँ प्रदान करता है। यह इन मीटिंगों के लिए अध्ययन करना है तथा पृष्ठभूमि तैयार करता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिरिक्त मंत्र के अन्य अंगों के लिए सचिवालय सम्बन्धी मेवाएँ प्रदान करना है तथा एक कार्यवाहिका की भाँति व्यवहार करना है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्यवाही के लक्ष्य की दृष्टि में यह विभिन्न माधनों द्वारा हर प्रकार की सूचना एकत्रित करना है।

महासचिव, चाटेंर के अनुच्छेद 97 के अनुसार संयुक्त राष्ट्रमंडल का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। वह मंत्र का मुख्य अंग है और इसलिए "मदस्य राज्यों के सांविधानिक व्यवहार का उत्तरदायित्व निभाने में उसका हाथ रहता है। मंत्र के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी के रूप में महासचिव ही लेखों, प्रारूप रिपोर्टों तथा अन्य आवश्यक तत्वों को तैयार करता है। इस शक्ति के बल पर महामन्त्र ऐसे कार्य करने में सक्षम है जो अप्रत्यक्ष रूप से अन्तिम निर्णयों को प्रभावित करे।"

महासचिव को न केवल प्रशासकीय अपितु राजनीतिक कार्य भी करने पड़ते हैं और इसीलिए उसे 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ' कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्रमंडल का भाग्य बहुत कुछ इस ध्यान पर निर्भर है कि महासचिव बुद्धि, चातुर्य और चरित्र-वत्ता में कितना सक्षम है। महासचिव की शक्तियाँ अनुच्छेद 99 में उल्लिखित हैं जिसके अनुसार उसे अधिकार है कि वह स्वयं सुरक्षा-परिषद् का ध्यान किमी ऐसे विवाद की ओर आकर्षित कर सकता है जिनके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा भंग होने का खतरा हो। श्री स्टीवन एम गेब्रल के अनुसार अनुच्छेद 99 के अन्तर्गत महासचिव को निम्नलिखित आठ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं—

1. महासचिव किसी भी विवाद अथवा स्थिति को सुरक्षा-परिषद् की सहाय्यी कार्य सूची में रख सकता है।

2. इस अनुच्छेद के आधार पर महामन्त्र राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम है।

3. महासचिव सुरक्षा-परिषद् के समक्ष उन आर्थिक और सामाजिक घटनाओं को प्रस्तुत कर सकता है जिनके राजनीतिक परिणाम निकलने की सम्भावना हो। इस प्रकार वह सुरक्षा-परिषद् और मंत्र के विभिन्न अंगों के बीच एक 'महत्वपूर्ण कड़ी' का काम करता है।

4. महासचिव को अधिकार है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व आवश्यक पूछताछ या जाँच-पड़ताल करे।

5. महासचिव यह निश्चय कर सकता है कि वह किस अन्तर्राष्ट्रीय समस्या को सुरक्षा-परिषद् के सामने रखे। परिषद् के सामने मामला पेश करने से पूर्व वह औपचारिक रूप से गुप्त वार्तालाप भी कर सकता है जिसे कभी प्रकाशित नहीं किया जाता।

6. महासचिव को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक घोषणा करने और सुझाव रखने का अधिकार है। वह चाहे तो सुरक्षा-परिषद् के विचारार्थ प्रारूप-प्रस्ताव भी रख सकता है।

7. महासचिव सुरक्षा-परिषद् के मध्य से विश्व लोकमत को सम्बोधित करते हुए शान्ति के लिए अपील कर सकता है। उचित समय पर की गई अपील बड़ी प्रभावकारी सिद्ध होती है।

8. अनुच्छेद 98 के अन्तर्गत महासचिव महासभा, सुरक्षा-परिषद्, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् तथा न्याय परिषद् की बैठकों में सचिव का कार्य सम्पन्न

करता है। महासचिव की रिपोर्टें, जो महासभा के अन्तिम सत्र में प्रस्तुत की जाती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इन रिपोर्टों में महासचिव का व्यक्तित्व बोलता है, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उसके दृष्टिकोण व्यक्त होते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति और घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। लियोनार्ड के अनुसार महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति के मन्देशों के समान प्रभावशाली है। महासभा में पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने में भी महासचिव का उल्लेखनीय सहयोग रहता है।

महासचिव को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के महान् अवसर प्राप्त होते हैं। यह विभिन्न देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों के साथ निरन्तर सम्पर्क में रहता है, अतः उसकी स्थिति ऐसी होनी है कि वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारों को प्रभावित कर सकता है। फिर भी अन्तिम रूप से सदस्यों का सहयोग महासचिव को असफल और सफल बना सकता है। महासचिव हिटलर, नेपोलियन, लिंकन या लॉयड जॉर्ज नहीं बन सकता। विश्व-संस्था के सदस्यों के विश्वास और सहयोग के अनुपात में ही उसकी शक्ति घटती-बढ़ती है। महासचिव एक निष्पक्ष अधिकारी समझा जाता है। वह एक अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक सेवक और विश्व का प्रवक्ता होता है। 2 जनवरी 1982 से पेरू के पेरिस दब्बारा महासचिव पद पर आसीन हैं।

शान्तिपूर्ण समाधान एवं प्रतिरोधात्मक अथवा बल-प्रयोग की प्रक्रिया

(Procedures for Peaceful Settlement and Procedures for Coercive Settlement)

चार्टर की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा कायम रखने के लिए मुख्यतः दो विधियाँ अथवा प्रक्रियाएँ व्यवहार में लाई जाती हैं—

- (1) शान्तिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाएँ (Procedures for Peaceful Settlement), एवं
- (2) बल-प्रयोग अथवा बाध्यकारी प्रक्रियाएँ (Procedures for Coercive Settlement)

शान्तिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाएँ

चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाएँ दी गई हैं। अनुच्छेद 33 में उल्लेख है कि यदि किसी विवाद में विश्व-शान्ति व सुरक्षा को खतरा हो और सम्बन्धित पक्ष अपना भगड़ा स्वयं निपटाने में असफल रहे तो सुरक्षा-परिषद् विवादों से चर्चा (Negotiation), जाँच (Enquiry), मध्यस्थता (Mediation), सौमनस्य या संराधन (Conciliation), पक्ष-निर्णय (Arbitration), न्यायिक समझौतों (Judicial Decisions), प्रादेशिक संस्थाओं या व्यवस्थाओं (Regional Agencies or Arrangements), अथवा

अपनी इच्छानुसार शान्तिपूर्ण उपायों (Other Peaceful Means of Their Own Choice) द्वारा विवादों को निपटाने के लिए कह सकती है।

वार्ता 'कूटनीति' का साधन है। यह एक वैधानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसकी सहायता से राज्य-सरकारें एक दूसरे के साथ अपने सम्बन्धों का संचालन करती हैं और मतभेदों पर विचार-विमर्श, उनका व्यवस्थापन और समाधान करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अरुणसह्यको की समस्या तथा नहरी-पानी विवाद को वार्ता द्वारा ही सुलझाया गया था। इस उपाय की सफलता दोनों पक्षों द्वारा समस्याओं के समाधान की लगन और ईमानदारी पर निर्भर है।

वाद-विवाद भी शान्तिपूर्ण समाधान की एक प्रभावी प्रक्रिया है सुरक्षा-परिपद या महासभा, कोई भी सिफारिश करने से पहले विवादी पक्षों को लिखित या मौखिक रूप से अपने दावे प्रस्तुत करने को आमन्त्रित कर उन्हें एक ऐसा अवसर देती है कि वे मुक्त रूप से अपनी शिकायतें रखें और द्वि-पक्षीय कूटनीति के माध्यम से ऐसी स्थिति में पहुँच जाएँ जहाँ विवाद के समाधानार्थ कोई समझौता हो सके। वाद-विवाद के मंच पर फँसकर कोई समस्या लम्बे अर्से तक उलझ भी सकती है।

जब समझौता-वार्ता द्वारा दो पक्षों में मतभेद नहीं सुलझने लगे तो तीसरा मित्र-राज्य अपनी मध्यस्थता द्वारा मतभेदों को मँत्रीपूर्ण ढंग से दूर करने में मदद कर सकता है। मध्यस्थता करने वाला पक्ष एक व्यक्ति या अन्तर्राष्ट्रीय निकाय भी हो सकता है। प्लानों एवं रिज का कथन है कि विवाद की समाधान-प्रक्रियाओं के लिए जो सिफारिशें सुरक्षा-परिपद या महासभा द्वारा की जाती हैं, उनमें अधिकारियों के उच्चतर स्तर पर द्विपक्षीय पुनर्वाताएँ, परामर्श, किसी संयुक्त राष्ट्रीय प्रायोग द्वारा जाँच एवं मध्यस्थता, किसी संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि या मध्यस्थ की नियुक्ति, किसी क्षेत्रीय अभिकरण को सन्दर्भित करना, पंच-निरणय, न्यायिक निर्णय आदि सम्मिलित हैं।

विवादों के निपटारे के एक अन्य साधन को सौमनस्य या संराधन (Conciliation) कहते हैं। इसमें वे विभिन्न प्रणालियाँ शामिल हैं जो तीसरे पक्ष द्वारा दो या अधिक राज्यों के विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अपनाई जाती हैं। संराधन की प्रक्रिया में विशेषकर तीन बातें सम्मिलित होती हैं—तथ्यों की जाँच मध्यक्षता एवं विवाद के लिए प्रस्तावों को प्रेक्षण। अनुच्छेद 34 और 36 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सुरक्षा-परिपद किसी ऐसे विवाद अथवा स्थिति की जाँच-पड़ताल कर सकती है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संधि का रूप से लेने अथवा कोई दूसरा विवाद उठ खड़ा होने की सम्भावना हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ जाँच एवं मध्यस्थता प्रायोग के माध्यम से अनेक समस्याओं को सुझाने की चेष्टा करता रहा है।

विवादों का न्यायिक समाधान अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम में होता है। चार्टर के अनुच्छेद 94 में यह व्यवस्था दी गई कि "सर का प्रत्येक सदस्य

किसी मामले में विवादी होकर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के फंसले को मानेगा।" कोरफूचनल विवाद (1949), हशाडेला टोरे विवाद (1951), एम्बेटेलियो का मामला, समुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए किसी राज्य का प्रवेश (1948) आदि मामले अथवा विवाद न्यायिक फंसले के आधार पर ही निपटाए गए थे।

कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिनमें समाधान में सुरक्षा-परिपद्, महासभा अथवा किसी आयोग की अपेक्षा कोई अनेक व्यक्ति मध्यस्थ या प्रतिनिधि के रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। परिपद् और महासभा के सभापतियों तथा महासचिव ने इस दृष्टि से अनेक अवसरों पर प्रभावशाली भूमिका निभायी है। 'अवरोधक कूटनीति' (Preventive Diplomacy) भी विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान का प्रभावशाली साधन है। इसके द्वारा शीतयुद्ध की स्थिति को सीमित और ज्ञान्त बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। अवरोधक कूटनीति का उद्देश्य विवाद में तनाव को कम करने और स्थिति को बिगड़ने से बचाना होता है। प्लानो एवं रिग्न ने समुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा अपनाई जाने वाली अवरोधक कूटनीति के उपायों को मोटे रूप में चार श्रेणियों में विभक्त किया है—(1) निरीक्षक गुप जो युद्ध-विराम विसंग्गीकृत क्षेत्र तथा अस्थायी युद्ध-विराम रेखाओं या सन्धि-भीमाओं का निरीक्षण करते हैं, (2) युद्धरत पक्षों के मध्य नियुक्त समुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ, (3) आन्तरिक सघर्ष के दमन करने और घरेलू व्यवस्था बनाए रखने में प्रयुक्त की जाने वाली समुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ तथा (4) साम्प्रदायिक समूहों में सशस्त्र सघर्ष को रोकने या सीमित करने में प्रयुक्त समुक्त राष्ट्रीय फोर्जे।

प्रतिरोधात्मक अथवा बल-प्रयोग की प्रक्रियाएँ

चार्टर के अध्याय 7 में जो व्यवस्थाएँ दी गई हैं, उनके अनुसार विश्व-शान्ति की सुरक्षा के लिए सकट उत्पन्न होने, शान्ति भंग होने अथवा विश्व के किसी भी क्षेत्र में सशस्त्र आक्रमण होने की दशा में समुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति एवं व्यवस्था की पुनर्स्थापना हेतु यदि आवश्यक समझे तो बल-प्रयोग कर सकता है अथवा प्रतिरोधात्मक उपायों का आश्रय ले सकता है। सघ बल-प्रयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान दो प्रकार से करने की चेष्टा करता है—प्रथम, वह जिसमें सशस्त्र सेना के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, एवं द्वितीय, जिसमें सशस्त्र सैन्य-बल का प्रयोग जरूरी हो जाता है। अध्याय 7 में अनुच्छेद 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 आदि प्रतिरोधात्मक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित हैं जिनका विवेचन सुरक्षा-परिपद् की शक्तियों के सन्दर्भ में किया जा चुका है। चार्टर की व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि विश्व-शान्ति और सुरक्षा कायम रखने अथवा पुनर्स्थापित करने के लिए सुरक्षा-परिपद् को सार्वधानिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाया गया है, तथापि कुछ ऐसी सार्वधानिक दुर्बलताएँ और जटिलताएँ विद्यमान हैं जिनके कारण परिपद् व्यवहार में आनातुल्य सफल निकाय सिद्ध नहीं हुई है। नियेपाधिकार के दुरुपयोग ने अनेक बार परिपद् की प्रभावकारी कार्यवाहियों में अवरोध उत्पन्न किया है। अब तक का इतिहास बताता है कि बड़े राष्ट्र, जो परिपद् के स्थायी सदस्य हैं, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष

रूप में बड़े विवादों के पीछे होने हैं और परिपक्व कोई कारगर उपाय तब तक काम में नहीं ला पाती जब तक उसे सभी बड़े राष्ट्रों का सहयोग न मिले। पुनर्रक्ष, चार्टर, में 'आत्मरक्षा' एवं 'आक्रमण' का भेद भी स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित नहीं है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की विश्व-शान्ति सम्बन्धी भूमिका (Role of the U. N. in World Peace)

अथवा

संघ का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव

(Impact of the U.N. on International Politics)

संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सम्मन्धों का समाधान करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को हर प्रकार से प्रोत्साहन देना है। यद्यपि संघ के आर्थिक और सामाजिक कार्यों का भी अप्रत्यक्ष रूप से विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में किए गए सद्कार्यों से शान्ति की शक्तियों को बल मिलता है और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का वातावरण विवर्धित होता है, तथापि संघ की राजनीतिक गतिविधियाँ ही सामान्यतः प्रकाश में आती हैं और निरव-जनमत बहुत कुछ उन्हीं के आधार पर उसकी सफलता-असफलता का मूल्यांकन करता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मुख प्रस्तुत सभी विषयों का वर्णन हमें संयुक्त राष्ट्रीय अभिलेखों में प्राप्त होता है जिनका ब्यौरा संयुक्त राष्ट्र की 'ईयर बुक्स' 'यूनाइटेड नेशन्स बुलेटिन', 'यूनाइटेड नेशन्स रिव्यू', 'यू एन मन्थली जौनियल' और संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पुस्तिकाओं भूमिका-पत्रों और शोध-पत्रों में मिलता है। महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट भी इसका कुछ परिचय करानी है।

1. रूस-ईरान विवाद—संयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया गया यह प्रथम विवाद था। ईरान के एक प्रान्त आइजरेजान में सोवियत सेनाएँ प्रवेश कर गई थी। 19 जनवरी, 1946 को ईरान ने सुरक्षा-परिषद् में शिकायत की। रूस पर ईरान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया और ईरान प्रान्त में रूसी सेनाओं की उपस्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा बताया गया। सुरक्षा-परिषद् में पश्चिमी गुट के राज्यों ने ईरान का समर्थन किया। जवाब में रूसी प्रतिनिधि ने परिषद् से प्रार्थना की कि यूनान में उपस्थित ब्रिटिश सैनिकों को निकालने के लिए कार्यवाही की जाए। अमेरिका और सोवियत रूस अपने शीत-युद्ध को संयुक्त राष्ट्रसंघ में पतीट लाए। रूस ने इसी विवाद में अपने प्रथम वीटो का प्रयोग किया। परिषद् ने रूस से आग्रह किया कि वह 6 मई, 1947 तक ईरान से अपनी फौजे हटा ले। वाद में मामला दोनों देशों की प्रत्यक्ष बातों द्वारा सुलभ गया। 21 मई, 1946 को दोनों देशों की राजधानियों में घोषणा की गई कि सोवियत सेनाएँ 9 मई को ही ईरान खाली कर चुकी हैं।

ईरानी सकट को सुलभाने में सुरक्षा-परिपद् का यद्यपि विशेष हाथ नहीं रहा, तथापि परिपद् में हुई बहसों ने रूस के विरुद्ध प्रबल जनमत जाग्रत कर दिया और रूस ने अपनी सेनाएँ ईरानी भूमि से हटा लेना ही उचित समझा। यह सिद्ध हो गया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकमत को प्रकाशित करने वाला एक अत्यन्त उपयोगी मंच है।

2. यूनान-विवाद—पहले 3 जनवरी, 1946 को रूस ने सुरक्षा-परिपद् से शिकायत की कि महायुद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी ब्रिटिश फौजे यूनानी भूमि पर बनी हुई हैं और यूनान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप एवं अन्तर्राष्ट्रीय तनाव पैदा कर रही है। परिपद् में विचार-विमर्श के समय यूनानी प्रतिनिधि ने कहा कि यूनानी जनता अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति अनिवार्य समझती है। इस स्थिति में स्वभावतः सुरक्षा-परिपद् ने मामले पर विचार समाप्त करने का निश्चय कर लिया। दिसम्बर, 1946 में यूनान ने परिपद् में शिकायत की कि पड़ोसी साम्यवादी देश छापामारों को सहायता दे रहे हैं और यूनान में तनाव पैदा कर रहे हैं। परिपद् द्वारा नियुक्त आयोग ने मई, 1947 में इस शिकायत की पुष्टि की। परिपद् ने जब आगे जाँच-पड़ताल करने का प्रयत्न किया तो सोवियत रूस ने वीटो का प्रयोग कर दिया। इसके बाद महासभा ने जाँच-पड़ताल के लिए आयोग नियुक्त किया जिसे अल्बानिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया ने अपनी सीमाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अन्त में तीन मुख्य कारणों से यूनानी समस्या का समाधान हो गया—

- (i) महासभा द्वारा नियुक्त आयोग की उपस्थिति में साम्यवादी देश छापामारों को पूरी सहायता नहीं दे सके।
- (ii) टोटो-स्टालिन-वाद के कारण यूनानी छापामारों को यूगोस्लाविया की सहायता बन्द हो गई।
- (iii) संयुक्त राष्ट्रसंघ के निरीक्षण में अमेरिका द्वारा यूनान को पूरी-पूरी आर्थिक व सैनिक सहायता मिली।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ सामयिक और साहसिक हस्तक्षेप से दक्षिणी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश साम्यवादी नियन्त्रण में जाने से बच गया।

3. बर्लिन की समस्या—1945 की पोट्सडम सम्मेलन के अनुसार बर्लिन नगर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के नियन्त्रण में विभक्त कर दिया गया था। पश्चिमी बर्लिन मित्र राष्ट्रों के नियन्त्रण में और पूर्वी बर्लिन रूस के नियन्त्रण में रहा। पोट्सडम सम्मेलन में यह भी तय हुआ था कि दोनों जर्मनी की आर्थिक एकरता वापस रखी जाएगी, लेकिन चारों देश इस निर्णय को वायम न रख सके। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा नई मुद्रा प्रचलित करने से शुरुआत होकर रूस ने 1 मार्च, 1948 को पश्चिमी बर्लिन के जल और स्थल मार्ग बन्द कर दिए। इस नाकेबन्दी का प्रत्युत्तर पश्चिमी राष्ट्रों ने हवाई मार्ग का अधिकाधिक प्रयोग करके दिया।

23 मितम्बर, 1948 को सुरक्षा-परिपद् में रूसी नाकेबन्दी के विरुद्ध शिकायत की गई और इस कार्यवाही को शान्ति के लिए धातुक बनाया गया। भगदा

महाशक्तियों के बीच था, अतः सुरक्षा-परिपक्व समस्या पर विचार करने के अनिवारित और कुछ भी कर सकने में असमर्थ थी। इसी बीच चारों महाशक्तियों से अनौपचारिक रूप से समस्या को सुलझाने की बातचीत चलती रही और 4 मई, 1949 को फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका ने सुरक्षा-परिपक्व को सूचित किया कि वलिन-समस्या पर हम से उनका समझौता हो गया है।

यद्यपि समस्या का हल महाशक्तियों के प्राप्त समझौते से हुआ, तथापि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विचार-विमर्श, पत्र-व्यवहार और सम्पर्क आदि के रूप में दोनों पक्षों को परस्पर मिलाने के लिए गहनत्वपूर्ण तथा उपयोगी पृष्ठभूमि तैयार की और स्थान तथा सुविधाएँ उपलब्ध की।

4 कोरिया संकट—इस गम्भीर संकट के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ को पहली बार सैनिक कार्यवाही का सहारा लेना पड़ा। जून, 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर भीषण सैनिक आक्रमण कर दिया। सुरक्षा-परिपक्व ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। जुलाई, 1950 में लगभग 16 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना तैयार की गई जिसने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। उत्तरी कोरिया के समर्थन में चीन भी लड़ाई में कूद पड़ा। एक ओर तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की सैनिक कार्यवाही जारी रही और दूसरी ओर संधि ने शान्तिपूर्ण समझौते के प्रयास भी चालू रखे। अन्त में जुलाई, 1961 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों से कोरिया का युद्ध विश्व-युद्ध बनने से रक गया। ए. ई. स्टोवेंसन के शब्दों में—“संयुक्त राष्ट्रसंघ की इस प्रथम महान् सामूहिक सैनिक कार्यवाही ने यह सिद्ध कर दिया कि यह संगठन शक्ति और शान्ति दोनों से काम लेने के योग्य है।” वास्तव में संयुक्तराज्य अमेरिका की प्रबल सैनिक शक्ति के बल पर ही संधि कोरिया युद्ध में सफल हो सका।

5 फिलिस्तीन विभाजन की समस्या—प्रथम महायुद्ध के बाद यह प्रदेश मंत्रित प्रदेश (Mandate) के रूप में ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त फरवरी, 1947 में ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि उसके लिए इस मंडेट के प्रशासन-प्रबल को चलाना सम्भव नहीं है। अप्रैल, 1947 में ब्रिटेन ने यह समस्या महासभा के सामने प्रस्तुत की। महासभा द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने अगस्त, 1947 में सिफारिश की कि फिलिस्तीन को दो भागों में बाँट दिया जाए—एक भाग में अरब राज्य की स्थापना हो और दूसरे में यहूदी राज्य की। महासभा ने सिफारिश स्वीकार कर ली, लेकिन फिलिस्तीन-विभाजन के प्रश्न पर अरबों और यहूदियों में संघर्ष बढ़ता गया। दोनों पक्षों में प्रभावी युद्ध-विराम के सभी संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रयास विफल हो गए। 14 मई, 1948 को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से अपना शासन-प्रबन्ध हटा लिया (जिसकी घोषणा 15 मई को की गई) और यहूदियों ने फिलिस्तीन में इजरायल-राज्य की घोषणा कर दी। बदले में ईराक, लेबनान, ट्रांसजोर्डन आदि अरब-राष्ट्रों ने फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया। अरब-राष्ट्र इजरायल के प्रत्यागमण को नहीं भैल सके। 11 जून, 1948 को संयुक्त राष्ट्रसंघीय

प्रतिनिधि वर्नाडोट के प्रयत्नों से दोनों पक्षों में चार सप्ताह के लिए युद्ध-विराम हो गया, किन्तु उपद्रव चलते रहे और 17 सितम्बर को वर्नाडोट भी गोली के शिकार हुए। सुरक्षा-परिपद ने अब्रुडों रातफ जे बुच को कार्यवाहक मध्यस्थ नियुक्त किया। 29 दिसम्बर को तीसरी बार युद्ध-विराम हुआ। इसके बाद महासभा ने एक 'संयुक्त राष्ट्र समझौता आयोग' (U N Conciliation Commission) नियुक्त किया जिसने अनेक गम्भीर प्रश्नों को सुलभाया और इजरायल व पड़ोसी राज्यों में सीमा-सम्बन्धी सन्धियाँ सम्पन्न हुईं।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों में फिलिस्तीन विभाजन की समस्या का समाधान होकर इजरायल और अरब राष्ट्रों में सन्धियाँ हो गईं, तथापि इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति की समस्या आज भी उन्नी की रंगो बनी हुई है। अक्टूबर, 1956 में मिस्र और इजरायल में पुनः युद्ध छिड़ा तथा रुसी हस्तक्षेप व राष्ट्रसंघीय प्रयासों से शान्ति स्थापित हुई। इसके बाद 1967 और फिर 1973 में अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच घमासान युद्ध हुआ, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रयत्नों से अस्थायी तौर पर शान्ति हो गई।

6 इण्डोनेशिया विवाद—द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इण्डोनेशिया पर हॉलैण्ड का अधिकार था। युद्धकाल में उस पर जापान ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जापान की पराजय के बाद इण्डोनेशिया के राष्ट्रवादियों ने अपने यहाँ एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी। इसके फलस्वरूप हॉलैण्ड और इण्डोनेशिया में युद्ध छिड़ गया। मामला सुरक्षा-परिपद में आया। परिपद द्वारा 'नियुक्त सद्भाव समिति' (Good Offices Committee) के प्रयत्नों से अगस्त, 1947 में दोनों पक्षों में युद्ध बन्द हो गया और स्थायी सन्धि की वार्ता आरम्भ हो गई, लेकिन दिसम्बर, 1948 में हॉलैण्ड ने इण्डोनेशियायी गणराज्य के विरुद्ध पुनः युद्ध छेड़ दिया तथा इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिपद ने इस कार्यवाही का विरोध करते हुए हॉलैण्ड से कहा कि इण्डोनेशिया में एक सर्वोच्च सत्ता-सम्पन्न संघात्मक गणराज्य की स्थापना की जाए जिसे डच सरकार 1 जुलाई, 1949 तक सम्प्रभुता हस्तांतरित कर दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'सद्भाव समिति' को 'इण्डोनेशिया आयोग' में परिवर्तित कर दिया गया।

बाफी विचार-विमर्श और दबाव के बाद हॉलैण्ड ने इण्डोनेशियायी राजधानी से अपनी फौजे वापस बुलाई और यह विचार प्रकट किया कि 30 दिसम्बर, 1949 तक इण्डोनेशिया-गणराज्य को सर्वोच्च सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। बाद में 27 दिसम्बर, 1949 को इण्डोनेशिया को एक स्वतन्त्र सम्प्रभु गणराज्य मान लिया गया और 28 दिसम्बर, 1950 को उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्रदान कर दी गई। इण्डोनेशियायी विवाद को हल करने में इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ को उत्तेजनात्मक सफलता प्राप्त हुई।

7. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का प्रश्न—दक्षिण अफ्रीका की सरकार 'वाले-तोरे' में भेद-भाव के लिए बहुत समय से बदनाम है। 1946 में

संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के प्रथम अधिवेशन में ही भारत ने यह प्रश्न उपस्थित कर दिया और दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर मानवीय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत की शिकायत पर यह सफाई दी कि यह उसका घरेलू मामला है और संयुक्त राष्ट्रसंघ को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महासभा ने दक्षिण अफ्रीका की आपत्ति को अमान्य ठहराते हुए भारतीय प्रस्ताव पारित कर दिया किन्तु दक्षिण अफ्रीका ने इस प्रस्ताव की कोई परवाह नहीं की और जाति-भेद की अपनी अमानवीय नीति चालू रखी। 1949 में यह प्रश्न पुनः महासभा में उठाया गया जिसने एक प्रस्ताव द्वारा सिफारिश की कि भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका एक गोलमेज सम्मेलन द्वारा समस्या का समाधान करें। सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की जिद के कारण कोई निर्णय न हो सका। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में अब तक यह प्रश्न बराबर उठाया जाता रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने अपना रुखा नहीं बदला है। महासभा में प्रस्ताव पारित होते हैं, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वास्तव में इस प्रकार के मानवीय व्यवहार की समस्या को न सुलझा पाना संयुक्त राष्ट्रसंघ की बहुत बड़ी विफलता है।

8. कश्मीर की समस्या—15 अगस्त, 1947 को भारत उप-महाद्वीप में दो स्वतन्त्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। स्वतन्त्रता देने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था की कि देशी राज्य अपनी इच्छानुसार अपनी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं और चाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। कश्मीर भी इसी तरह का एक देशी राज्य था। इस राज्य ने स्वतन्त्र रहने का निर्णय किया।

पाकिस्तान की नीयत कश्मीर को जबरदस्ती अपने साथ मिलाने की थी। अतः 22 अक्टूबर, 1947 को उसने उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त के कबाइलियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। पाकिस्तान की नियमित सेना के एक बड़े भाग ने भी इस पर आक्रमण में भाग लिया। राजधानी श्रीनगर का पतन सन्निकट होने पर कश्मीर के महाराजा ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारत सरकार से कश्मीर को भारत में शामिल कर अधिलम्ब सैनिक सहायता देने का अनुरोध किया। महाराजा ने 'प्रवेश-पत्रक' (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर कर दिए। तत्पश्चात् भारतीय सेनाएँ कश्मीर की रक्षा के लिए भेज दी गईं। कश्मीर में पाकिस्तान का नग्न आक्रमण जारी रहा और 1 जनवरी, 1948 को भारत ने सुरक्षा-परिपद में शिकायत की कि इस आक्रमण से अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान का कश्मीर पर आक्रमण स्वयं भारत पर आक्रमण है। भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पण्डित नेहरू ने घोषणा की कि कश्मीर का भारत में त्वासी विलय 'जगमत-सग्रह' (Plebescite) के आधार पर होगा।

सुरक्षा-परिपद में दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप होने लगे। 20 जनवरी, 1948 को सुरक्षा-परिपद ने एक मध्यस्थता आयोग (Mediation

Commission) नियुक्त किया जिसे युद्धबन्दी और जनमत-संग्रह का कठिन काम सौंपा गया। आयोग के प्रयत्न से युद्ध-विराम हो गया और नु कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। आयोग ने जनमत-संग्रह कराने के लिए दोनों देशों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जिन्हें पाकिस्तान ने मंजूर कर दिया। कश्मीर में परिस्थितियाँ तेजी से बदलती गईं और भारत व पाकिस्तान में समझौता कराने के संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रयास सफलता प्राप्त न कर सके। पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों का खुला समर्थन मिलता रहा और उनके हाथों में खेलते हुए सुरक्षा-परिपद भारत के साथ अन्याय करती रही। 1954 में कश्मीर-संविधान सभा ने कश्मीर के भारत में विलय का विधिवत् अनुमोदन कर दिया। 1956 में राज्य के लिए एक नया संविधान स्वीकार किया गया जिसके द्वारा कश्मीर प्रत्येक दृष्टि से भारत का बंधन बन गया। इस तरह कश्मीर समस्या का स्वरूप विलकुल बदल गया और जनमत-संग्रह का कोई मूल्य नहीं रह गया। पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल हो जाने के कारण और कश्मीर को बलपूर्वक लेने की चालें खेनने के कारण जनमत-संग्रह की बात बहुत पहले ही निरर्थक हो चुकी थी।

पाकिस्तान पाश्चात्य राष्ट्रों के समर्थन के चल पर बार-बार कश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा-परिपद में उठाता रहा, लेकिन भारत के दृढ़ रत और न्याय का पक्ष लेते हुए सोवियत रूस के निवेधाधिकार प्रयोग के कारण उसके कुटिल उद्देश्य पूरे नहीं हो सके।

कश्मीर का मामला आज भी सुरक्षा-परिपद की विषय-सूची में है। दुर्भाग्यवश विश्व की गुटबन्दी के कारण सुरक्षा-परिपद अभी तक इस विवाद को हल नहीं कर सकी है। सुरक्षा-परिपद में पश्चिमी शक्तियों का बहुमत है और पाकिस्तान परिपद के फैसले को अपने पक्ष में कराने का कोई मौका नहीं चूकता। किन्तु सितम्बर, 1965 और दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्धों के बाद अब स्थिति इतनी बदल चुकी है कि पाकिस्तान भी यह ममन्न हुआ है कि परिपद के माध्यम से भारत पर कोई भी निर्णय थोपने की बात सोचना व्यर्थ होगा।

वास्तव में संयुक्त-राष्ट्रसंघ के लिए कश्मीर का विवाद राष्ट्र के समान सिद्ध हुआ। यद्यपि यह इस प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्धों को शान्त करने में सफल हुआ है, तथापि पश्चिमी शक्तियों के हाथों में खेनने हुए उमने जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है उससे इस महान् सस्या के गौरव को आघात ही पहुँचा है। न्याय और निष्पक्षता का तकाजा यही है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ आक्रमण पाकिस्तान की सेनाओं को कश्मीर की भूमि से हटाने की कार्यवाही करे।

9 स्वेज नहर विवाद—1869 में निर्मित स्वेज नहर का संचालन एक स्वेज नहर कम्पनी करती थी जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अधिपति शेयर थे। समझौते के अनुसार इसकी रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी सेना रखती थी। नवम्बर, 1950 में मिस्र की सरकार ने यह माँग की कि ब्रिटिश सेना स्वेज नहर क्षेत्र में हट जाए। ब्रिटेन द्वारा यह माँग टुकरा देने पर दोनों पक्षों के सम्बन्ध बहुत

हो गए। मित्र में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया और अन्त में जुलाई, 1954 में एक नए समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन को स्वेज नहर क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेनी पड़ी। इस समय मित्र में कर्नल नासिर का शासन था। उपर्युक्त समझौते के बाद भी मित्र और ब्रिटेन व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हुआ और 26 जुलाई, 1956 को नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा मित्र स्थित स्वेज नहर कम्पनी की सम्पत्ति जप्त कर ली। 26 सितम्बर को ब्रिटेन और फ्रांस ने यह सम्पूर्ण विवाद सुरक्षा-परिषद् के समक्ष रखा। 13 अक्टूबर, 1956 को परिषद् ने समस्या के हल के लिए एक प्रस्ताव के रूप में 6 सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिसमें स्वेज नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रखने का भी सुझाव दिया गया, लेकिन सोवियत वीटो से यह प्रस्ताव रद्द हो गया।

आपासी तनाव इतना बढ़ गया कि 26 अक्टूबर, 1956 को ब्रिटेन और फ्रांस की प्रेरणा पर इजरायल ने स्वेज नहर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इसके दो दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस भी इजरायल के साथ युद्ध में कूद पड़े। सुरक्षा-परिषद् में युद्ध बन्द करने का प्रस्ताव फ्रांस और ब्रिटेन के वीटो के कारण पास नहीं हो सका। संधि के जीवन में यह घोर संकट का समय था जब सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य स्वयं संधि के चार्टर का उल्लंघन कर संधि के एक सदस्य-राज्य पर हमला कर रहे थे। 2 नवम्बर, 1956 को महासभा के एक विशेष अधिवेशन ने अमेरिका का एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस की सैनिक कार्यवाही की निन्दा कर अविलम्ब युद्ध बन्द करने पर जोर दिया गया। 4 नवम्बर को यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि महासचिव थोडॉस हेमरशोल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक आपात्कालीन सेना तैयार करे जो मित्र में जाकर युद्धबन्दी का कार्य करे। 10 राष्ट्रों ने मिलकर 6 हजार सैनिक दिए जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के नीले और श्वेत ध्वज के नीचे एकत्र हुए। 5 नवम्बर को सोवियत रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक निश्चित समय के भीतर मित्र पर हमला बन्द नहीं किया गया तो सोवियत संधि नवीनतम शस्त्रों के साथ इस संकट में हस्तक्षेप करेगा। इस चेतावनी से तृतीय महायुद्ध की सम्भावना दिखाई पड़ने लगी और ब्रिटेन और फ्रांस ने भयभीत होकर युद्ध बन्द कर दिया। 7 नवम्बर, 1956 को महासभा ने अपने प्रस्ताव में कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस व इजरायल की सेनाएँ मित्र से हट जाएँ तथा स्वेज नहर क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की व्यवस्था की जाए। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप युद्ध पूरी तरह बन्द हो गया और 15 नवम्बर को संयुक्त राष्ट्रसंघीय आपात्कालीन सेना का पहला दस्ता मित्र पहुँच गया। मित्र ने संधि की सेनाओं की तभी प्रवेश की आज्ञा दी जब मित्र की प्रभुसत्ता को हानि न पहुँचाने का वचन दे दिया गया। अप्रैल, 1957 में स्वेज नहर द्वारा अहाजों का आना-जाना पुनः आरम्भ हो गया।

मित्र में युद्ध बन्द कराने और विदेशी सेनाओं को हटाने में संयुक्त राष्ट्रसंघ की पूरी सफलता मिली और स्वेज पर ब्रिटेन व फ्रांस के पुनः आधिपत्य के सपने चूर-चूर हो गए।

10 कांगो समस्या—सघ की सबसे कठिन परीक्षा कांगो में हुई और सौभाग्यवश इसमें वह सफल हुआ। जुलाई, 1960 में कांगो में भीषण गृह-युद्ध छिड़ गया जिसे भड़काने में बेल्जियम का मुख्य पड़पन्त्र था। कांगो सरकार की प्रार्थना पर संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेनाओं ने पहुँचकर कांगो और बेल्जियम के बीच होने वाले संघर्ष को तो समाप्त कर दिया, लेकिन कांगोई प्रांतों के गृह-युद्ध की स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक ओर तो सैनिक उपाधों द्वारा कांगो का विपटन रोका तथा दूसरी ओर समझौतावादी नीति भी अपनाई। सितम्बर, 1962 में महासचिव हेमरशोल्ड कांगो के संघर्षरत नेताओं से बातचीत करने के लिए स्वयं कांगो गए और वहीं मार्ग में वायु-दुर्घटना में मारे गए। नए महासचिव ऊथार्ट ने अपने प्रयत्न जारी रखे। अन्त में विरोधी प्रान्त कांगो ने अपने घुटने टेक दिए और जनवरी, 1963 में कांगो में शान्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ का शान्ति-स्थापना का कार्य कांगो के एकीकरण के साथ समाप्त हुआ।

11. यमन की समस्या—19 सितम्बर, 1962 को यमन के शासक इमाम अहमद की मृत्यु हो गई। 26 सितम्बर को एक क्रान्ति द्वारा यमन में राजतन्त्र की समाप्ति कर दी गई और क्रान्तिकारी परिषद् ने वहाँ गणराज्य की स्थापना की। दूसरी ओर राजतन्त्रवादियों को अपने पक्ष में कर शहजादे हुसैन ने सऊदी अरब में जिद्दा नामक स्थान पर यमन की निर्वासित सरकार की स्थापना की। दोनों यमनी सरकारें एक दूसरे को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक और सामरिक नीतियाँ अपनाती रही। अक्टूबर के समाप्त होते-होते राजतन्त्रवादियों और गणतन्त्रवादियों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। सऊदी अरब और जोर्डन ने राजतन्त्रवादियों की सहायता की और मिस्र ने गणतन्त्रवादियों की। गृह-युद्ध को व्यापक बनने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने हस्तक्षेप किया। मार्च, 1963 में संघ की ओर से राल्फ बुच ने व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा दोनों पक्षों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे अपने-अपने सैनिकों को वापस बुला लें और समस्या का शान्तिपूर्ण हल खोजें। संयुक्त राष्ट्रसंघ के वाद के प्रभावपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप शनैः-शनैः बाह्य शक्तियों ने यमन से अपनी सेनाएँ हटा ली और अन्त में वहाँ शान्ति स्थापित हो गई।

12 साइप्रस की समस्या—13 अगस्त, 1960 को साइप्रस ब्रिटिश अधिकार से मुक्त होकर स्वतन्त्र गणराज्य बना। साइप्रस का जो मविधान बनाया गया उसमें वहाँ के बहुसंख्यक यूनानियों और अल्पसंख्यक तुर्कों के बीच सामञ्जस्य और शान्ति स्थापित रखने की व्यवस्था की गई। स्वतन्त्रता के कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति मकारियोस ने संविधान में ऐसा संशोधन प्रस्तावित किया जिससे दोनों जातियों के मध्य स्थापित सन्तुलन और सामञ्जस्य समाप्त हो जाना। फलस्वरूप दोनों जातियों में राजनीतिक संघर्ष और गृह-युद्ध की शुरुआत हो गई। समस्या के समाधान के लिए यूनान, टर्की और साइप्रस के बीच इंग्लैंड में शान्ति-सम्मेलन शुरू हुआ। ब्रिटेन ने साइप्रस में नाटो फौजें भेजने का कुछ जाल रचा। राष्ट्रपति मकारियोस ने दिसम्बर, 1963 में मारा मामला सुरक्षा-परिषद् के सामने प्रस्तुत

वर संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक भेजने और स्थिति सम्भालने के लिए सभ के हस्तक्षेप की माँग की। सन्धे विचार-विमर्श के बाद मार्च, 1964 में साइप्रस में शान्ति-स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना भेजने का निर्णय किया गया। शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय सेना साइप्रस पहुँच गई जिसने वहाँ कानून और व्यवस्था कायम रखने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद इस आपात्कालीन सेना की भववि बढाई जाती रही।

13. डोमिनिकन गणराज्य विवाद—लेटिन अमेरिका के इस छोटे से राज्य में अप्रैल, 1965 में गृह-युद्ध छिड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पक्ष की सरकार को बचाने के लिए सैनिक हस्तक्षेप किया। बहाना यह लिया गया कि डोमिनिकन गणराज्य को साम्यवादियों से सुरक्षित रखने के लिए यह कार्यवाही की गई है। कम ने सुरक्षा-परिपद् से अनुरोध किया कि वह मामले में हस्तक्षेप करे। अन्त में परिपद् द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि दोनों युद्धरत पक्ष युद्ध-विराम करे और महासचिव डोमिनिकन गणराज्य में आवश्यक जाँच-पड़ताल के लिए प्रतिनिधि भेजे। अमेरिकी राज्यों के संगठन ने भी समस्या के समाधान की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए। अन्त में अमेरिकी राज्यों के संगठन और संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों से 4 माह के गृह-युद्ध के पश्चात् 31 अगस्त, 1965 को दोनों पक्षों में समझौता हो गया और शान्ति स्थापित हो गई। महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में दृढ़ शब्दों में कहा कि डोमिनिकन गणराज्य में युद्ध बन्द कराने के कार्य में सभ ने अति महत्वपूर्ण भाग लिया है।

14. अरब-इजरायल संघर्ष—1956 के अरब-इजरायल संघर्ष में युद्ध-विराम होने पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्तर्राष्ट्रीय सेना गाजा और मिस्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हो गई थी ताकि इजरायल व अरबों में पुनः संघर्ष न छिड़ जाए, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता गया। 1967 में युद्ध की तैयारियाँ जोरों से शुरू हो गईं। मई में राष्ट्रपति नासिर के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के सैनिक हटा लिए गए। अब संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सेनाएँ आमने-सामने घा गईं। एक दूसरे की कार्यवाहियों से स्थिति बिगड़ गई और 5 जून को एकाएक इजरायल ने अरबों पर विनाशकारी आक्रमण कर दिया। जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, ईराक आदि 10 करोड़ वाली जनसंख्या के देश छोटे से इजरायल का आक्रमण सह न सके। केवल 5 दिन की लड़ाई में ही अरब-राष्ट्रों की सामरिक क्षमता का विनाश हो गया। इस बीच सुरक्षा-परिपद् युद्ध-विराम के लिए पूरे प्रयास करती रही। 7 जून को परिपद् ने यह आदेशात्मक प्रस्ताव पारित किया कि सभी युद्धरत देश युद्ध बन्द कर दें। चूँकि अरब-राष्ट्र युद्ध-क्षमता खो चुके थे और इजरायल सामरिक उद्देश्यों को पूरा कर चुका था, अतः 8 जून को इजरायल और मिस्र के बीच युद्ध-विराम हो गया और 10 जून तक सभी अरब-राष्ट्रों और इजरायल के बीच पूरी तरह लड़ाई बन्द हो गई। संयुक्त अरब-गणराज्य स्वेज तट पर संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक रखने के लिए सहमत हो गया। 16 जुलाई से स्वेज

नहर क्षेत्र में सघ पर्यवेक्षकों की देख-रेख में युद्ध-विराम लागू हो गया किन्तु फिर भी पूर्ण शान्ति स्थापित न हो सकी और आज भी इस क्षेत्र में दोनों पक्षों में सैनिक झड़पें होती रहती हैं। आपसी तनाव पुनः विस्फोटक स्थिति में पहुँचता जा रहा है और स्थायी शान्ति की कोई आशा दिखाई नहीं देती। अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच बार-बार युद्ध-विराम कराने में सघ को सफलता अवश्य मिली है, लेकिन इसे समस्या का स्थायी समाधान नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में शान्ति तभी सम्भव हो सकेगी जब विश्व की महाशक्तियाँ बीच में पड़कर रचिपूर्वक कोई हल निकालने का प्रयत्न करेंगी।

15. भारत-पाक संघर्ष, 1965—कश्मीर को हटाने के लिए पाकिस्तान ने 1965 में पुन युद्ध का आश्रय लिया। अगस्त 1965 में हजारों पाकिस्तानी हमलावर छिपकर युद्ध-विराम रेखा पारकर कश्मीर के भारतीय प्रदेश में घुस गए। भारत ने जब इस घुसपैठ को नाकामयाब कर दिया तो सितम्बर, 1965 को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तानी एक पूरी पैदल ब्रिगेड और 70 टैंक कश्मीर पर चढ़ आए। विवश होकर भारत को भी अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध खुलकर लड़ाई छेड़ देनी पड़ी। 22 दिन के घमासान युद्ध में पाकिस्तान पर करारी मार पड़ी और आखिर संयुक्त राष्ट्रमण्डल के प्रयासों से 23 सितम्बर, 1965 को प्रातः 3½ बजे भारत-पाक युद्ध-विराम हो गया तथा पाकिस्तान की रही-सही लाज जाने से बच गई।

संयुक्त राष्ट्रमण्डल प्रारम्भ से अन्त तक युद्ध-विराम के प्रयत्न करता रहा। स्वयं महासचिव ने दिल्ली और कराँची पहुँच कर श्री शास्त्री और अयूब से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया। महासचिव ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में सुरक्षा-परिषद् को सूचित किया कि यदि पाकिस्तान सहमत हो तो भारत बिना शर्त युद्ध बन्द करने को प्रस्तुत है, किन्तु पाकिस्तान ने युद्ध-विराम प्रस्ताव को प्रत्यक्षतः ठुकरा दिया। महासचिव ने माँग की कि परिषद् दोनों पक्षों को अविलम्ब युद्ध बन्द करने का आदेश दे और युद्ध बन्द होने पर आवश्यक कार्यवाही करे। भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि परिषद् पहले यह निश्चिन करे कि आन्नामक वीन है। भारत ने यह भी बना दिया कि संयुक्त राष्ट्रमण्डलीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्टें स्वयं इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं। पाकिस्तान ने पहले कश्मीर में घुसपैठ शुरू की और बाद में विधिवत् आक्रमण कर दिया। अन्त में काफी ऊहापोह के बाद परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि भारत और पाकिस्तान 21 मितम्बर को दोपहर में युद्ध बन्द कर दें और युद्ध-विराम लागू होने के बाद अपनी सेनाओं को 5 अगस्त, 1965 की स्थिति में लौटा लें। पाकिस्तान द्वारा सहमति की सूचना देने पर युद्ध 23 मितम्बर, 1965 को प्रातः 3½ बजे बन्द हो गया।

सुरक्षा-परिषद् का 22 मितम्बर का प्रस्ताव भारत के साथ अन्याय था। हमें दोनों देशों को युद्ध बन्द करने का आदेश दिया गया था जबकि यह आदेश

केवल आन्तर्गणनीय पाकिस्तान को ही दिया जाना चाहिए था। क्योंकि उसने ही परिपद के युद्धबन्दी के पूर्ववर्ती प्रस्ताव को ठुकराया था। आश्रामक और आश्रान्त दोनों के साथ एक-सा व्यवहार करना न्यायमग्न नहीं था। भारत ने केवल यही मोचकर इसे स्वीकार कर लिया कि उसकी शान्तिप्रियता पर कोई अगुली न उठा सके।

16. चेकोस्लोवाकिया का संकट—21 अगस्त, 1968 को मोवियत संघ तथा वारसा-गण्डि के अन्य साम्यवादी देशों ने चेकोस्लोवाकिया में सैनिक कार्यवाही कर हंगरी की घटनाओं को एक बार फिर ताजा कर दिया। रूसी पक्ष की इस सैनिक कार्यवाही के कारण ये। मूल कारण यह घोषित किया गया कि चेकोस्लोवाकिया के साम्यवादी शासन को प्रतिनिध्यावादी तत्वों में बचाने के लिए सैनिक हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। तुरन्त ही इस मसले को मुरझा-परिपद में उठाया गया। परिपद के 7 सदस्य-राष्ट्रों की ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें रूसी कार्यवाही को स्वतन्त्र और प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र पर आन्तर्गण बनाकर उसकी निन्दा की गई तथा यह माँग की गई कि रूस और वारसा राष्ट्रों की सेनाएँ शीघ्र ही चेकोस्लोवाकिया से वापस चली जाएँ। कई कारणों में यह प्रस्ताव व्यर्थ सिद्ध हुआ। स्वयं चेकोस्लोवाकिया की सरकार ने इस प्रस्ताव पर विरोध किया। बाद में तत्तत्त्वर में महासभा के अधिवेशन में इस विवाद को पुनः उठाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन इस बार भी कोई परिणाम नहीं निकला। वास्तव में चेकोस्लोवाकिया-संकट के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक मूकदर्शक से अधिक कोई भूमिका नहीं निभाई।

17. साम्यवादी चीन का संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश—महासभा द्वारा सन् 1971 के अधिवेशन में साम्यवादी चीन की संघ की सदस्यता से सम्बन्धित एक चर्चा ही उलझे हुए प्रश्न का समाधान कर दिया गया जो 22 वर्षों से चला आ रहा था। 26 अक्तूबर, 1971 को साम्यवादी चीन को संघ की सदस्यता प्रदान करने और ताइवान (राष्ट्रवादी चीन) का उससे निष्कामित करने सम्बन्धी प्रस्तावना का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 75 मतों से स्वीकार कर लिए जाने से संयुक्त राष्ट्रसंघ के इतिहास में वस्तुतः एक नए युग का सूत्रपात हुआ।

18. बंगला देश की समस्या—पाकिस्तान ने अपने ही एक भाग पूर्वी बंगाल की स्वायत्तता की माँग को कुचलने के लिए 1970-71 के दूबरे दमन चक्र चलाया जिसके फलस्वरूप मार्च, 1971 में पूर्वी बंगाल की जनता ने एक स्वतन्त्र देश के रूप में अपनी स्थापना की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने बंगला देश के जन-आन्दोलन को कुचलने के लिए अमानुषिक ढंग से सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जिसके कारण लगभग एक करोड़ व्यक्ति भाग कर शरणार्थियों के रूप में भारत आ गए। भारत ने तथा अन्य देशों के साथ स्वयं बंगला देश के प्रतिनिधि मण्डल ने इस समस्या की गम्भीरता की ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अमेरिका के

पाक-समर्थक और बंगलादेश विरोधी रुख के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ इस समस्या को सुलझाने और बंगलादेश में पाकिस्तान द्वारा मानवीय अधिकारों के हनन को रोकवाने में कोई विशेष सहायता नहीं कर सका। पाकिस्तान का भीषण अनाचार और हत्याकाण्ड जारी रहा तथा विश्व-संस्था उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकी। बाद में भारत के सहयोग से बंगलादेश का मुक्ति-संग्राम सफल हुआ और एक सम्प्रभु राज्य के रूप में वह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बन गया।

19 पारत-पाक संघर्ष, 1971—इस संघर्ष के समय भी संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अमेरिका और उसके पिछले गठबन्धु राष्ट्रों के प्रभाव में आकर पुनः बड़ा पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया। भारत के इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि असली विवाद पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच है तथा इसे पारत-पाक विवाद का रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

सुरक्षा-परिषद् में अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि भारत तथा पाकिस्तान युद्ध-विराम करें और तुरन्त अपनी-अपनी सेनाएँ पीछे हटा लें। अन्य राष्ट्रों द्वारा भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिनमें से एक में युद्ध-विराम कर सेनाएँ वापस हटाने की बात थी। चौथा प्रस्ताव रूस द्वारा पेश किया गया जिसमें कहा गया कि पूर्वी पाकिस्तान का राजनीतिक हल निकाला जाए जो स्वाभाविक रूप से अन्त में संघर्ष को समाप्त करेगा। अमेरिका के प्रस्ताव पर रूसी वीटो के प्रयोग से भारत के समक्ष उपस्थित एक भारी सकट टल गया। 24 घण्टे के भीतर ही परिषद् की दूसरी बैठक में पुनः युद्ध-विराम तथा दोनों पक्षों के सैनिकों के लौट जाने का प्रस्ताव किया गया जिसे रूस ने पुनः वीटो कर दिया। चीन ने अपने असफल प्रस्ताव में भारत पर आक्रमण करने का आरोप लगाया। सुरक्षा-परिषद् में असफल होने पर विवाद महासभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों के प्रभाव से युद्ध-विराम तथा सेनाओं की वापसी का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी युद्ध-विराम तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक बंगलादेश के मुक्ति-ग्रान्दोलन को और वहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान की फौजों की वापसी की बात को नहीं माना जाता। 14 दिसम्बर को परिषद् की तीसरी बैठक में अमेरिका के पहले जैसे ही प्रस्ताव पर रूस ने तीसरी बार वीटो का प्रयोग किया। परिषद् की अगली बैठक बुलाई जाने और कोई अन्य प्रपच किए जाने से पूर्व ही भारत ने एक पक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दी (16 दिसम्बर)। भारत का उद्देश्य बंगलादेश गणतन्त्र को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्ति दिलाना था। यह उद्देश्य पूरा होने ही उसने युद्ध-बन्दी का आदेश दे दिया और युद्ध में बुरी तरह पिट रहे पाकिस्तान ने युद्ध बन्द कर देने में ही अपनी कुशलता समझी।

20. अरब-इजरायल युद्ध, 1973—अक्टूबर, 1973 में चौथा अरब-इजरायल युद्ध छिड़ गया, लेकिन महाशक्तियों की उदासीनता के कारण सुरक्षा-परिषद् में तत्काल सारी स्थिति पर विचार नहीं हो सका। रूस ने इसलिए दिलचस्पी

नहीं ली कि युद्ध के प्रारम्भ में जीत अरबों की रही थी। अमेरिका ने दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि वह उस अवसर के इन्तजार में था जब इजरायल सम्भल कर जवाबी हमले द्वारा अपना पक्ष मजबूत कर लेता। इसी बीच संयुक्त राष्ट्रमण्डल के महासचिव वाल्टेर्होम ने सुझाव रखा कि युद्धरत राष्ट्रों से तटार्थ अविलम्ब बन्द करने की अपील की जाए। 7 अक्तूबर को सुरक्षा-परिषद् की गुप्त बैठक में इस सुझाव पर विचार हुआ, लेकिन रूस और चीन के विरोध के कारण कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सका। अधिकांश सदस्यों का विचार था कि ऐसी भी अपील का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक उसके साथ यह माँग भी न की जाए कि इजरायली फौजें 1967 की युद्ध-पूर्व की विराम रेखा तक लौट जाएँ। 9 अक्तूबर को अमेरिका ने सुरक्षा-परिषद् की बैठक बुलाने की पहल की। अपने प्रस्ताव में उसने माँग रखी कि इजरायल, मिस्र और सीरिया में युद्ध बन्द करने और युद्ध की पूर्वस्थिति तक अपनी-अपनी फौजें लौटा लेने की अपील की जाए। यह प्रस्ताव अरब देशों के हित में नहीं था अतः रूस ने प्रारम्भ में ही कह दिया कि वह ऐसे किसी भी प्रस्ताव को 'वीटो' कर देगा। परिषद् की प्रथम बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और 12 अक्तूबर की दूसरी बैठक में भी इस प्रश्न पर कोई सहमति न हो सकी कि युद्ध किस प्रकार बन्द कराया जाए। जब युद्ध की स्थिति अत्यधिक विस्फोटक हो गई तो 22 अक्तूबर को रूस और अमेरिका ने संयुक्त रूप से सुरक्षा-परिषद् में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सुरक्षा-परिषद् यह माँग करती है कि युद्धरत पक्ष तुरन्त युद्ध बन्द कर दें और जो जिस जगह है वहाँ इस प्रस्ताव की स्वीकृति के 12 घण्टे के अन्दर सारी फौजी कार्रवाहों को रोक दे; युद्धबन्दी के तुरन्त बाद सुरक्षा-परिषद् के 1967 के 24वें प्रस्ताव को पूरी तरह लागू किया जाए एवं सम्बन्धित पक्ष न्यायोचित तथा स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए समझौता-वार्ता प्रारम्भ कर दें परिषद् के प्रस्ताव को इजरायल और मिस्र ने 22 अक्तूबर की शाम को 7 बजे स्वीकार कर लिया, लेकिन सीरिया ने इसे नहीं माना, अतः गोलन पहाड़ियों पर भीषण युद्ध जारी रहा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रूस का अध्यक्ष हस्तक्षेप होने की सम्भावना हो गई। 26 अक्तूबर को अमेरिका ने भी विश्व भर अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दे दिया। 27 अक्तूबर को सुरक्षा-परिषद् की बैठक में युद्ध-विराम की निगरानी के लिए और उसके उल्लंघन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आपात् सेवा के गठन पर विचार-विमर्श हुआ और परिषद् ने भारत के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महासचिव ने कहा कि आपात् सेवा में 7 हजार व्यक्ति होंगे। मित्र में युद्ध-विराम के उल्लंघन को रोकने के लिए एक सैनिक टुकड़ी अविलम्ब ही तैनात कर दी गई। इसके बाद पश्चिमी-एशिया की विस्फोटक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। समझौता-वार्ता चालू रही और तब अन्त में 11 नवम्बर, 1973 को इजरायल और मिस्र के बीच एक 6 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। संयुक्त राष्ट्रमण्डल की भूमिका से पुनः यह स्पष्ट हो गया कि वह महाशक्तियों के हाथ का किनारा मात्र है।

21 ईरान और ईराक युद्ध (सितम्बर-अक्टूबर, 1980)—ईरान और ईराक में सैनिक झड़पें तो पहले से ही हो रही थी, किन्तु सितम्बर, 1980 के उत्तरार्द्ध में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध छिड़ गया। सुरक्षा परिषद् ने 2 सितम्बर, 1980 की रान सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव में ईरान व ईराक से तत्काल युद्ध बन्द करने तथा आपसी मतभेदों को हल करने के लिए बाहरी मदद स्वीकार करने को कहा। सुरक्षा-परिषद् के प्रस्तावों और स्वयं महासचिव के प्रयत्नों का ईरान-ईराक मध्यम पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। मार्च, 1982 के अन्त तक प्राप्त समाचारों के अनुसार दोनों देशों में अब भी छुट-पुट लड़ाई जारी है और राजनीतिक क्षेत्र मयुक्त राष्ट्र से कोई विशेष उम्मीद नहीं करते।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की राजनीतिक गतिविधियों के इस विवेचन से स्पष्ट है कि संघ ने विवादों का समाधान करने में अपनी जागरूकता दिखाई है लेकिन वह महाशक्तियों की अड़भेराजी का शिकार रहा है। कश्मीर के प्रश्न, विद्वतनाम के संघर्ष, दक्षिण अफ्रीका की रणभेद नीति, निःशस्त्रीकरण अणुशक्ति के प्रयोग पर प्रतिबन्ध, पश्चिमी एशिया के संकट के स्थायी समाधान आदि में संघ की विफलता का ही मुँह देखा पड़ा है फिर भी उनमें से कुछ समस्याओं को अधिक विस्फोटक बनने से रोकने की दिशा में संघ के प्रयास प्रशंसनीय रहे हैं। अनेक अवसरों पर संघ के सामयिक हस्तक्षेप के कारण ही स्थिति विस्फोटक होने से रकी है। यद्यपि संघ विश्व-शान्ति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पूर्ण सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुआ है तथापि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में इसने शान्ति-स्थापना के अनेक बार सकल प्रयत्न किए हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की विशिष्ट एजेंसियाँ और

संस्थाएँ : गैर-राजनीतिक कार्य

(Specialized Agencies and Institutions of the U. N. :

Non-political Functions)

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान और युद्धों को रोकना ही संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक मात्र कार्य नहीं है, चार्टर के अनुसार उनका यह भी दायित्व है कि वह मनुष्यमात्र की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए प्रयत्नशील हो। पिछड़े देश गरवता से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का निवारण करके बालान्तर में विश्व-शान्ति के लिए तत्परताक सिद्ध होते हैं, घत. उन्हें अपनी दुरावस्था में मुक्त करने के लिए विश्व-संस्था को प्रत्यक्ष-परोक्ष गैर-राजनीतिक कार्य भी करने पड़ने हैं। साधन के अभाव में विकासशील राष्ट्र एक तो अपने वांछित प्रयत्न करने में अग्रमर्थ रहते हैं और दूसरी ओर विकसित राष्ट्रों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। यह स्थिति स्थायी युद्धों को जन्म देने वाली अथवा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को घाघान पहुँचाने वाली होती है घत: विश्व-संस्था का यह दायित्व है कि विश्व-शान्ति को स्थायी बनाने के लिए समाज के विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान दे। वह विश्व में सामाजिक न्याय के लिए प्रयत्न करे, सामाजिक विकास और

स्वास्थ्य की दशा पर ध्यान दे, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रता के प्रति राष्ट्रों और व्यक्तियों के मन में विश्वास उत्पन्न करे तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए सबेष्ट रहे। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सांविधानिक निर्माणकर्त्ता किसी प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के इन दायित्वों से भली भाँति परिचित थे और इसीलिए उन्होंने संघ के चार्टर में इस प्रकार की अनेक व्याख्याएँ दी हैं जिनके आधार पर विश्व में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमताओं को दूर करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। चार्टर के अनुच्छेद 55 में उल्लेख है कि "स्थायित्व तथा कल्याणकारी स्थितियों के निर्माण की दृष्टि से, जो लोगों के समान अधिकारों और आत्म-निर्णयों के सिद्धान्त पर आधारित राष्ट्रों के मध्य शान्तिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए आवश्यक हैं, संयुक्त राष्ट्रसंघ निम्नलिखित बातों को प्रोत्साहन देगा—

(अ) जीवन के उच्च स्तर तथा आर्थिक एवं सामाजिक न्यायालय और विकास की स्थितियों की स्थापना;

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-सामाजिक-स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी सहयोग, एवं

(स) विना जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव किए मानव अधिकारों और आधारभूत स्वतन्त्रताओं के लिए सार्वदेशिक सम्मान और उनके पालन की व्यवस्था।"

इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ अपनी स्थापना के समय से ही प्रयत्नशील है। इस दृष्टि से कुछ अभिकरणों की भी स्थापना की गई है, जैसे—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O.), (2) खाद्य एवं कृषि संगठन (F.A.O.), (3) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.), (4) संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), (5) विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.), (6) अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी (I.A.E.A.), (7) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I.F.C.), (8) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ (ICAO), (9) विश्व डाक संगठन (W.P.U.), (10) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (ITU), (11) विश्व श्रद्धा विज्ञान संगठन (WMO), (12) विश्व शरणार्थी संगठन (U.N.H.C.R.), (13) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक आदि।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की दुर्बलताएँ

(Weak Points of the U.N.O.)

1. संघ अभी तक सार्वदेशिक संगठन नहीं बन सका है। दोनों जर्मनी, वियतनाम, दोनों कोरिया आदि राष्ट्र अभी तक संघ से बाहर हैं। प्रायः देखा गया है कि विश्व-संस्था से बाहर रहने वाले देश अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के उत्तरदायित्व से स्वयं को मुक्त समझते लगते हैं संघ की कार्य-क्षमता पर जिसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2. मध्य सैद्धान्तिक विरोधाभास का शिकार है। एक ओर राज्यों के समानाधिकार और समान प्रभुसत्ता की बात कही गई है तो अनेक स्थलों पर चार्टर में

राज्यों की सम्प्रभु असमानता का सह-अस्तित्व है। उदाहरणार्थ, सुरक्षा-परिषद् में स्थायी सदस्यों की स्थिति असामान्य रूप से विशेषाधिकार-युक्त है। चार्टर में लक्ष्यों और सिद्धान्तों के गीत गाए गए हैं पर कहीं भी न्याय, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, राष्ट्रीय आत्म-निर्णय जैसे सिद्धान्तों की व्याख्या नहीं की गई है।

3 घरेलू क्षेत्राधिकार की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है और यह भी उल्लेख नहीं है कि 'घरेलू क्षेत्र' का निश्चय कौन करेगा। इस बारे में महासभा के निर्णय प्रायः गुटबन्दी के आधार पर होते रहे हैं, वस्तुस्थिति के आधार पर नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में 'घरेलू क्षेत्राधिकार' और 'हस्तक्षेप' की विशिष्ट कल्पना है, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ विशुद्ध राजनीतिक विषय बना हुआ है।

4. संयुक्त राष्ट्रसंघ 'यथास्थिति सम्बन्धी अस्पष्टता' के कारण भी कुछ कम प्रभावशाली रहा है। वास्तव में जर्मनी, कोरिया, पूर्वी यूरोप, वियतनाम आदि सभी अस्थायी व्यवस्थाओं के परिणाम हैं और यथास्थिति को कायम रखने के बारे में बहुत अस्पष्टता है। फलस्वरूप प्रभावशाली और निश्चित कार्यवाही करने की दृष्टि से संघ प्रायः अस्थिर रहा है।

5. संघ के बाद-विवाद और निर्णय अधिकांशतः पक्षपातपूर्ण अथवा महाशक्तियों के हितों और निर्णयों से प्रभावित रहे हैं। अधिकांश समस्याएँ शक्ति राजनीति द्वारा तय की जाती हैं। पश्चिमी गुट के बहुमत के प्रत्युत्तर के लिए रूस अपने निवेधाधिकार का बहुलता से प्रयोग करता है। स्वयं महासचिव यह स्वीकार करते रहे हैं कि गुटबन्दी और बड़े राष्ट्रों के संघर्ष ने विश्व-संस्था को पगु बना दिया है।

6. संघ निवेधाधिकार के दुरुपयोग का मञ्च बना हुआ है। स्थायी सदस्य किसी भी उचित, किन्तु अपने से विरोधी दावे को विशेषाधिकार के प्रयोग से अमान्य ठहरा देते हैं। यह विचित्र स्थिति है कि कोई एक महाशक्ति शेष सदस्यों की इच्छाओं को दबा दे और यहाँ तक कि महासभा की इच्छा पर भी कुठाराघात करदे पर वह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ मामलों में इस निवेधाधिकार की व्यवस्था से ही न्याय की रक्षा हो सकी है, जैसे कश्मीर के मामले में या भारत-पाक संघर्षों के समय।

7. महासभा विश्व-जनमत का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उसके निर्णय का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वस्तुतः 'शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव' पारित किए जाने के बाद भी व्यवहार में महासभा आज भी अपनी उपयोगिता में बहुत कुछ सुरक्षा-परिषद् पर आश्रित है। यदि महासभा किसी कार्य की सिफारिश दो-तिहाई बहुमत से भी करे तो परिषद् उसे अपने विवेक के आधार पर अस्वीकार कर सकती है। यह एक गम्भीर सांविधानिक विरूपता है कि एक ही समय में दो पक्ष प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष रूप प्रकट कर सकते हैं। शक्ति-विनिराज में महाशक्तियों की मनमानी को कायम रखने की व्यवस्था के फलस्वरूप संघ में 'सुरक्षा-परिषद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सरकार' की स्थिति बनी हुई है।

8. संघ के पास अपने निर्णयों को व्यवहृत कराने की स्वयं की शक्ति नहीं है। उसके पास 'काटने के लिए दांत' नहीं है। उसकी निजी सेना नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को खतरा पैदा होने पर वह सदस्य-राष्ट्रों की सैनिक सहायता पर निर्भर रहती है। यह सदस्यों की मर्जी पर है कि वह सैनिक सहायता दे या न दें।

9. संघ के निर्णयों का महत्त्व सिफारिशों से अधिक कुछ नहीं है। सदस्य-राष्ट्रों को छूट है कि वे उन्हें स्वीकार करे कि ठुकरा दें। एक बड़ी दुर्बलता यह है कि महासचिव की शक्तियों को भी अभी तक समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जा मना है। अतः परिपक्व द्वारा प्रस्ताविन कार्यवाही करना कई बार महासचिव के लिए कठिन हो जाता है।

10. चार्टर में आत्म-रक्षा और आक्रमण के बीच भेद स्पष्ट नहीं किया गया है। यह साफ तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है कि किसी देश द्वारा किए जाने वाले किस प्रकार के कार्य आक्रमण माने जाएंगे। चार्टर के अनुसार आक्रमण का अर्थ 'शक्ति का अवैधानिक प्रयोग' है, किन्तु 'शक्ति का अवैधानिक प्रयोग' क्या है, यह प्रश्न विवादास्पद है।

उल्लेखनीय है कि अब, लगभग 51 वर्षों के परिधम के बाद आक्रमण की परिभाषा 350 शब्दों की कर दी गई है। हिन्दुस्तान दिनांक 16 दिसम्बर, 1974 के अनुसार—

"संयुक्तराष्ट्र महासभा ने आक्रमण की परिभाषा की, जो 8 अनुच्छेदों में की गई है, सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

आक्रमण की परिभाषा तय करने के लिए राष्ट्र और राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत विद्वान् राजनीतिक विशेषज्ञ सन् 1923 से काम कर रहे थे।

आक्रमण की परिभाषा के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि आक्रमण एक देश द्वारा दूसरे देश की प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता या राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध सशस्त्र सेना का प्रयोग है या किसी अन्य तरीके का प्रयोग, जो संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अनुरूप नहीं है।

दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्तराष्ट्र घोषणापत्र का उल्लंघन कर एक देश द्वारा दूसरे देश पर पहले सशस्त्र सेना का प्रयोग आक्रमण की कार्यवाही का प्रारम्भिक सञ्चालन होगी, यद्यपि सुरक्षा-परिपक्व संयुक्तराष्ट्र घोषणापत्र के अनुरूप यह निश्चित कर सकती है कि आक्रमण हुआ है।

तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि युद्ध की घोषणा किए बिना भी एक देश द्वारा दूसरे देश पर सशस्त्र आक्रमण, दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करना चाहे अस्थायी ही क्यों न हो, बमबारी, बन्दरगाहों व तटों की नाकेबन्दी भी आक्रमण है। एक देश की सशस्त्र सेना द्वारा दूसरे देश की जमीन, समुद्र, वायु सेना, नौसेना और विमानों के बड़े पर धावा बोलना भी आक्रमण के अन्तर्गत है। समझौते की अवधि के बाद भी दूसरे देश की भूमि पर जमे रहना आक्रमण की कोटि में आता है।

किसी तीसरे देश के विरुद्ध अपनी भूमि का प्रयोग करने की अनुमति देना या किसी दूसरे देश की ओर से किसी अन्य देश पर सशस्त्र कार्यवाही के लिए सशस्त्र गिरोह व भाड़े के सैनिक भेजना भी आक्रमण है।

चौथे अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा-परिपद भी यह तय कर सकती है कि घोषणापत्र के अन्तर्गत किन-किन कार्यवाहियों को आक्रमण की सजा दी जा सकती है।

पाँचवें अनुच्छेद के अन्तर्गत आक्रमण, आक्रमणही होगा। इसमें इस बात पर कोई विचार नहीं होगा कि राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों से दूसरे देश पर आक्रमण के लिए मजबूर होना पड़ा है।

आक्रमणकारी युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के प्रति एक अपराध है। आक्रमण से अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी बँट जाती है।

आक्रमण के परिणामस्वरूप मिले क्षेत्र या कोई अन्य सुविधा बँध नहीं मानी जाएगी।

छठे अनुच्छेद में कहा गया है कि इस परिभाषा का अर्थ यह नहीं होगा कि मयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्र में वृद्धि या कमी की जा सकती है।

सातवें अनुच्छेद में आत्म-निर्णय, स्वाधीनता और स्वतन्त्रता के अधिनार की लड़ाई आक्रमण की परिभाषा में नहीं आएगी।

आठवें अनुच्छेद में कहा गया है कि आक्रमण की परिभाषा सम्बन्धी आठो अनुच्छेद एक दूसरे से सम्बद्ध हैं।"

11. महासभा की कार्य-विधि भी दोषपूर्ण है। सभा के सम्मुख बाद-विवाद योग्य विषयों की संख्या पहले ही बहुत अधिक रहनी है और इस पर भी सन्धे-जम्हे भाषणों द्वारा सभा का अधिकांश समय नष्ट कर दिया जाता है। इसके अनिर्णित ममिनियों के समक्ष प्रस्ताव भी कभी-कभी पुनः सभा में पेश कर दिए जाते हैं। इस पुनरावृत्ति से लाभ कम होता है, समय की हानि अधिक।

12. महासभा के अधिवेशनों में राष्ट्रों के प्रमुख राजनीतिज्ञ उपस्थित रहने की परवाह नहीं करते और साधारण प्रतिनिधियों के उपस्थित रहने से सभा की कार्यवाही अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाती।

13. सभ के बाहर की गई सैनिक सन्धियों के कारण भी इसका महत्व कुछ कम हो गया है। विवसीराइट ने ठीक ही लिखा है, "क्षेत्रीय सुरक्षा-गुटों के अनियन्त्रित विकास से मयुक्तराष्ट्र चार्टर के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती।"

14. यह भी एक विडम्बना है कि मदस्वर्ण महासभा और सुरक्षा-परिपद का प्रयोग प्रचार-मस्वा के रूप में करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कलाबाजियों द्वारा विश्व-जनमत को अनुचित रूप से अपने पक्ष में तैयार करना होता है। नार्मन बंटविच और फ्रड्रूय मार्टिन के दन शब्दों में वजन है कि "महासभा और सुरक्षा-परिपद का प्रयोग भगडो को मुलभाने के लिए नहीं, अपितु कई बार भगडो को बढ़ाने के लिए किया जाता है।"

संघ की शक्तिशाली बनाने के सुझाव (Suggestions to Strengthen the U. N. O.)

नवीन और परिवर्तित परिस्थितियों में यह मान्यता हो गयी है कि प्रश्न तो संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में प्रापञ्चिक संशोधन दिया जाए और द्वितीय, उस प्रकार के विभिन्न उपाय काम में लाए जाएँ जिनसे यह विश्व-संस्था अधिक शक्तिशाली बन सके। पहले उन सुझावों का उल्लेख किया जाएगा जो चार्टर में संशोधन के लिए प्रस्तावित किए जाते रहे हैं और तत्पश्चात् अन्य सुझावों का।

(क) चार्टर में संशोधन अथवा पुनर्विरीक्षण—महाराष्ट्रियों के बीच पारम्परिक महपति न होने से चार्टर में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं हो सका है। यह धारणा की जाती है कि संशोधन से वर्तमान शक्ति-सन्तुलन बिगड़ जाएगा और संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों से अन्तर्राष्ट्रीय मनभेद प्रसार रूप में उत्पन्न प्राण्य ग्यापि समन-समय पर अनेक संशोधन सम्बन्धी सुझाव दिए जाने रहे हैं जिनमें से प्रमुख ये हैं—

1. महासभा में प्रतिनिधित्व के तरीके में परिवर्तन दिया जाए। एक देश के 5 सदस्य और एक वोट के स्थान पर सदस्य गया वोट जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए ताकि महासभा के निर्णय अधिकतर जनसंख्या के हितों के आधार पर हों।

2. सुरक्षा-परिषद् की निष्पत्ति की शक्ति बढ़ा दी जायें अथवा उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान करे। केवल महासभा को इस प्रकार सदस्यता प्रदान करने का अधिकार दिए जाने से सदस्यता के प्रश्न पर राजनीतिक मोड़बाजी की वर्तमान दुरावस्था समाप्त हो जाएगी।

4. सुरक्षा-परिषद् में स्थायी सदस्यों का प्रावधान हटा देना चाहिए ताकि शक्ति-सन्तुलन पश्चिमी शक्तियों के पक्ष में न रहे। परिषद् की सन्तुलित और निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय जगत् के भागन जैसे सदस्यपूर्ण सदस्यों की भी इनमें समान आधार पर स्थान मिले। यदि ग्यापी सदस्यों को कायम रखने का निश्चय हो तो उनकी सदस्य-शक्ति बढ़ाई जाए।

5. 'घरेलू क्षेत्र' की व्यवस्था में समुचित सन्तुलन दिया जाता चाहिए। यह सुझाव भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में जो बातें घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं उनका सहिताकरण कर दिया जाए तथा उनके अनिर्णित जो विषय भेप रहे उन पर शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रसंघ जो कार्यवाही उचित समझे स्वतन्त्रतापूर्वक करे।

6. यह सुझाव दिया जाता है कि महासभा द्वि-सदनात्मक होनी चाहिए— एक 'मानवता का सदन' हो और दूसरा 'राष्ट्रीय सदन'। मानवता-सदन का संगठन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में हो तथा राष्ट्रीय सदन या सदन राज्यों की समानता के आधार पर हो और उसमें प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र की प्रतिनिधित्व दिया

जाए। सभी साधारण विषयों का निर्णय दोनों के द्वारा किया जाए, लेकिन मतभेद की स्थिति में वह निर्णय उसी रूप में मान्य समझा जाए जिस रूप में मानवता-सदन पुनः तीन-चौथाई मतों से उसे पारित करदे। साथ ही शान्ति और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय मानवता-सदन द्वारा लिया जाए। इस बात के निर्णय का दायित्व कि कौन-से विषय महत्वपूर्ण हैं, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया जाए।

7 सुरक्षा-परिपद की बैठके हमेशा न होकर कुछ निश्चित अवधियों में ही हो ताकि सम्बन्धित देशों के प्रधान मन्त्री या विदेश मन्त्री उसमें भाग ले सकें। यह सुभाव विशेष स्वागत योग्य नहीं है, क्योंकि सुरक्षा-परिपद यदि एक सतत् कार्यशील अंग न रहा तो शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा होने पर अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की वर्तमान क्षमता जो कुछ भी है उसमें बाधा पहुँचैगी।

8. अनुच्छेद 27 में सुरक्षा-परिपद में मतदान की व्यवस्था में 'प्रक्रिया सम्बन्धी विषय' तथा 'अन्य सभी विषय' शब्द इतने अनिश्चित और अस्पष्ट हैं कि इससे निषेधाधिकार का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। अतः यह उपयुक्त है कि इन शब्दों को अधिष्ठ स्पष्ट किया जाए।

9. प्रादेशिक संगठन सम्बन्धी धाराओं में ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे सैनिक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन न मिल सके।

10. शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णय राष्ट्रों पर बाध्यकारी माने जाएँ, पर यह भी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए कि निर्णय राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हों।

(ख) अन्य सुझाव—समय-समय पर जो अन्य सुझाव दिए गए हैं उनमें से कुछ ये उल्लेखनीय हैं—

1. सदस्य-राज्य अपने उत्तरदायित्वों को अधिक स्वामिभक्ति और रचनात्मक ढंग में पूरा करें। महाशक्तियाँ विशेष रूप से सत्र के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहे और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सैद्धान्तिक शिथिलता न बरतें।

2 महासभा, सुरक्षा-परिपद तथा अन्य अंगों को प्रचार-संस्था के रूप में काम में ल लाया जाए। इस सम्बन्ध में एक तो सदस्य-राज्य स्वयं नियन्त्रण रखें और दूसरे आवश्यक सांविधानिक व्यवस्थाएँ करने का भी प्रयास किया जाए।

3 महासभा के अधिवेशन अल्पकालीन हो जिनमें सदस्य-राष्ट्रों के प्रधान-मन्त्री अथवा विदेश मन्त्री सम्मिलित हों। मन्त्रि-मण्डलीय स्तर के प्रतिनिधि अपने-अपने देशों की निर्धारित नीति के लिए उत्तरदायी होते हैं, अतः वे महासभा की कार्यवाही को अधिक प्रभावशाली और निर्णायकारी बनाने में सक्षम हो सकते हैं।

4 चार्टर की व्याख्या करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। सुरक्षा-परिपद की शक्तियों के मूल्य पर यदि महासभा, जो विश्व-जनमन की प्रतिनिधि है, कोई कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले, तो इसका विरोध नहीं किया

जाना चाहिए। मुख्य लक्ष्य तो समस्या का समाधान करना है न कि वैधानिक प्रवर्णनको उत्पन्न कर समस्या को उत्पन्न करना।

5. संघ के वर्तमान यन्त्र को विस्तृत बना देना चाहिए ताकि आवश्यकता-नुसार नवीन समस्याओं का निर्माण किया जा सके।

6. जो क्षेत्र राष्ट्रीय सम्प्रभुता के बाहर हैं वही पर प्रशासकीय मत्ता स्थापित कर लेनी चाहिए, जैसे बाह्य अन्तरिक्ष।

7. संघ की आय का कोई स्वतन्त्र स्रोत होना चाहिए। अतः उचित होगा कि वह विकास-कर, सेवा-कर, यात्री-कर आदि लगाए और विश्व बैंक की आय तथा बाह्य अन्तरिक्ष की फीस आदि द्वारा अपनी आय में वृद्धि करे।

मूल्यांकन

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुए लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। इन 35 वर्षों में उसका इतिहास-चित्र विचित्र रहा है। कुछ समस्याएँ उसने हल की और कुछ उसके मञ्च पर पहुँच कर सुनभने के बजाए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के चक्क्यूह में फँसकर और भी उत्पन्न गईं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना भावी मन्त्रालियों की युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए की गई थी। निःसन्देह इन 35 वर्षों में संसार की तृतीय विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, भले ही केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ ही इसके लिए धैर्य का एकमात्र अधिकारी न हो। बड़े राष्ट्रों ने शक्तिशाली परमाणु-आयुधों से जो विनाश-शक्ति संचित कर ली है, उनमें भी विश्व-युद्ध को रोका है। कोई राष्ट्र आज इसलिए महायुद्ध प्रारम्भ नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए जो मंहारक शक्ति वह प्रयोग में लाएगा वह उसके प्रतिपक्षी को ही नहीं स्वयं उसे भी जिनष्ट कर देगी। परन्तु केवल आत्म-विनाश के इस भय ने ही नहीं, संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच पर शान्ति के समर्थक देशों ने शक्ति के पक्ष में जो बातावरण उत्पन्न किया है, उसने भी महायुद्ध को रोका है, फिर भी यह दुःख की बात है कि छोटे-मोटे युद्ध संसार में चलते ही रहे हैं और संयुक्त राष्ट्रसंघ उन्हें रोकने में सफल नहीं हुआ है। जहाँ तक विश्व के देशों के आपसी विवादों का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यतः बाद-विवाद के मंच का काम ही करता रहा है। इस मंच पर सबे होकर पक्ष-विपक्ष में लोगों ने अपनी भड़ास निकाली है और भड़ास निकल जाने से वे विवाद अनेक बार ठण्डे पड़ गए हैं। विवादों के कभी-कभी उत्पन्न होने का एक कारण यह है कि बड़ी शक्तियाँ न्याय और सत्य की उपेक्षा कर अपने हानि-लाभ की कसौटी पर हर सवाल को परखती हैं और तदनुसार अपने निषेधाधिकार के हथियार (अधिकार) का प्रयोग करती हैं। जिस निषेधाधिकार को अन्याय का निवारक होना चाहिए था, अनेक बार वह स्वयं अन्याय में सहायक बना है।

इन तीन दशकों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्वरूप में एक बुनियादी परिवर्तन आ गया है। पहले जहाँ संयुक्त राष्ट्रीय मंच पर दो ही राष्ट्र-समूह थे, वहाँ आज गुट-निरपेक्ष और विकासशील देशों का समूह भी एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर

कर सामने आ गया है। बड़ी शक्तियाँ आज इस समूह की उपेक्षा नहीं कर सकती। अपनी एकाधिक्रमफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व के लिए एक आशा की किरण है, इसीलिए आज उसके सदस्यों की संख्या 156 हो गई है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ को यदि महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त हो तो यह संस्था विश्व की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। पश्चिमी एशिया तथा साइप्रस में शान्ति की स्थापना जैसी बड़ी समस्याओं का निदान राष्ट्रसंघ के प्रत्यक्ष तत्वावधान में ही सम्भव है। संयुक्त राष्ट्रसंघ को उपनिवेशवाद के उन्मूलन में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इण्डोनेशिया, मोजम्बिक, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया आदि को स्वतन्त्र बनाने में संघ के प्रयत्न अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। संघ की संरक्षण व्यवस्था ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में वृद्धि की है और विश्व के अनेक प्रदेशों के निवासियों में स्वशासन की योग्यता विकसित करने में सहायता पहुँचाई है। कुछ वर्ष पूर्व संघ की न्याय पद्धति के अन्तर्गत 11 देश थे जो अब स्वतन्त्र राज्यों के रूप में विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठित हैं। संघ अफ्रीका में बचे हुए साम्राज्यवादी उपनिवेशों की स्वतन्त्रता के लिए मत्त प्रयत्नशील रहा है।

गैर-राजनीतिक कार्यों में संघ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण और सफल रही है। इसकी विभिन्न संस्थाओं से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों और समाजों को भारी लाभ पहुँचा है। अम सगठन ने श्रमिकों की दशा को उन्नत करने और खाद्य तथा कृषि संगठन ने अन्न का उत्पादन बढ़ाकर अकाल की नियन्त्रित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीमारियों के प्रतिकार में और यूनेस्को ने मानव के सांस्कृतिक विकास में बहुत सहायता पहुँचाई है। संघ के गैर-राजनीतिक कार्यों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक राज्याध्यक्ष के ये शब्द निश्चय ही सही हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में निःशस्त्रीकरण और राजनीतिक कार्यों का खरोश तो अभी अपनी ही ले रहा है जबकि उसकी विशेष संस्थाओं की सहायता और सहयोग का बहुधा अपनी धीमी चाल से बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने जन, धन और अन्नरक्ष का प्रयोग मानव-जाति के हित में करने पर निरन्तर बल दिया है। संघ अन्नरक्ष अनुसन्धान के लिए सहायता दे रहा है। संघ देवी प्रयोग के समय भी सक्रिय होता जा रहा है। बाढ़, सूकान, अकाल और भूकम्प से होने वाले विनाश से राहत पहुँचाने में संघ ने अनेक अवसरों पर बड़ी तत्परता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्रमन महापना एवं विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी अनेक संस्थाएँ बना रहा है जो मानव-विकास के लिए कार्यरत हैं। इन समस्याओं में प्रमुख हैं—यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संघ, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संघ, विश्व अनु-शक्ति संस्था और संयुक्त राष्ट्र संघीय वाणिज्य एवं व्यापार विकास सम्मेलन। नीचे अधिक देशों को विकास कार्यों के लिए हजारों मिलियन डॉलर की सहायता दी गई है। इसके अलावा लनिज पदार्थों की खोज में भी सहायता दी जा रही है। माय ही मय गोप्यता आहार, पौष्टिक तत्व, पुस्तक विमर्श, चिकित्सा आदि का कार्य भी कर रहा है। इनका ही नहीं, विश्व की बढ़ती आबादी की

रोकथाम के लिए परिवार-नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 से भी अधिक देशों को सान्नों डॉलर प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रमण्डल के अनुमान के अनुसार वर्तमान शताब्दी के अन्त तक संसार की जनसंख्या लगभग साढ़े 7 अरब तक पहुँच जाएगी। संयुक्त राष्ट्रमण्डल ने आरम्भ से ही भारत के विकास कार्यों में दिलचस्पी दिखाई है।

अन्तिम विश्लेषण के रूप में यह कहना होगा कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की राजनीतिक और नैर-राजनीतिक उपलब्धियों का पता इसकी असफलताओं की तुलना में बहुत अधिक भारी है। यदि महाशक्तियों द्वारा हम विश्व-संस्था को मुक्त हृदय से सहयोग दिया जाए, निषेधाधिकार का सख्त और विवेक सम्मत प्रयोग किया जाए, सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उसमें भारत जैसे महान् देश को स्थान दिया जाए, साम्राज्यवादी और पूंजीवादी देशों के एकाधिकार पर प्रभावी रोक लगाने की दशा में प्रयत्न किए जाएँ, तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता में चार चाँद लग जाएँगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ का बदलता हुआ रूप आशा की नई किरणों को उजागर कर रहा है। इस विश्व संघा पर लगभग 20 वर्ष से संयुक्तराज्य अमेरिका छाया हुआ था, पर अब उसकी मज्जामानी का अन्त हो रहा है। शोषित और पीड़ित एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देश अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मञ्च के प्रभावशाली अभिनेता बनते जा रहे हैं। वह दिन समाप्त हो चुका है जब अमेरिका और उसके पिछलग्गू राष्ट्र विश्व संस्था को अपनी 'बपौनी' मानकर चलते थे।



वियतनाम की समस्या और पश्चिमी एशिया में समस्या-क्षेत्र (The Problem of Vietnam and Problem Areas in West Asia)

पश्चिमी एशिया और वियतनाम विश्व-राजनीति के दो महान् बिस्फोटक केन्द्र रहे हैं। इन दोनों ने अनेक श्रवसरो पर महायुद्ध तक का खतरा उपस्थित किया है। पश्चिमी एशिया आज भी बिस्फोटक है और जब तक इजरायल और अरब राष्ट्रों के बीच अन्तिम रूप से स्थायी शान्ति-सन्धि नहीं हो जाती, तब तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक अशान्ति-स्थल बना रहेगा। वियतनाम युद्ध का अन्त 30 अप्रैल, 1975 को वियतनामी जनता की विजय के साथ ही चुका है, लेकिन धार्मिक पुनर्निर्माण की विकट समस्या अभी सामने है।

वियतनाम की समस्या

(The Problem of Vietnam)

वियतनाम द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक

लगभग 1,27,000 वर्गमील और 3 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला वियतनाम कभी हिन्द-चीन का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। 19वीं शताब्दी में हिन्द-चीन पर फ्रांस के अधिकार के समय वियतनाम भी फ्रांस के अधिनियंत्रण में चला गया। 1940 में वियतनाम पर जापान ने अधिकार कर लिया। जापानी आधिपत्य के दौरान वियतनाम में राष्ट्रवादी आन्दोलन और साम्यवादी तत्त्वों की भूमिगत गतिविधियाँ तेज हो गईं। इनका संगठन 'वियत-मिन्ह-लीग' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और छापामार नेता होची-मिन्ह को नेतृत्व सौंपा गया। 9 मार्च, 1945 को जापानियों ने फ्रांसीसी सेनाओं को पूरी तरह सदेह कर हिन्द-चीन की स्वाधीनता का एलान कर दिया। अगस्त, 1945 में वियत-मिन्ह-लीग को सत्ता सौंप दी गई। इस नए 'वियतनाम लोकतान्त्रिक गणराज्य' के राष्ट्रपति होची-मिन्ह बने। बायोशई ने (जो अग्रिम का भूतपूर्व मन्त्रि-प्राधान्य था और जिम्मे महायुद्ध के समय वियतनाम की स्वाधीनता की घोषणा कर स्वयं को वियतनाम का शासक घोषित कर दिया था) होची-मिन्ह द्वारा हुनोई में स्थापित की गई कार्यकारी सरकार के 'महोच्च राजनीतिक परामर्शदाता' का पद प्राप्त करके मन्तोप कर लिया। गेर-बाग्युनिस्टों का होची-मिन्ह की विचारधाराओं और व्यक्तित्व के सामने टिक पाना

मुश्किल था। होची-मिन्ह से अलग विचारधारा रखने वाले लोगों ने वियतनाम के दूसरी ओर जमा होना शुरू किया। ये लोग अपने-आपको राष्ट्रवादी कहते थे। इन राष्ट्रवादियों में भी परस्पर तनाव और सन्देह बढ़ने लगा। 6 सितम्बर, 1945 को इस शेष क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने पुनः शासन स्थापित कर लिया। 6 मार्च, 1946 को हनोई और फ्रांसीसी मुख्य प्रायुक्त ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार वियतनाम लोकतान्त्रिक गणराज्य को हिन्द-चीन महासंघ के अन्तर्गत एक स्वाधीन सरकार स्वीकार किया गया।

वियतनाम का विभाजन : जेनेवा समझौता

उपर्युक्त समझौते के बावजूद दोनों पक्षों में लड़ाई जारी रही। सैनिक साधनों द्वारा होची-मिन्ह पर विजय पाने में अपने-आपको नाकामयाब पाकर फ्रांस ने राजनीतिक साधनों का आश्रय लिया। उसने असन्तुष्ट बायोदाई को अन्तर्गत में एक नई कार्यकारी सरकार (Provisional Government) स्थापित करने के लिए उकसाया। 5 जून, 1948 को बायोदाई ने कोचीन-चीन सहित 'रिपब्लिक ऑफ वियतनाम' के नाम से एक नई सरकार गठित की। इस तरह अब वियतनाम में दो सरकारें काम करने लगी—दक्षिण वियतनाम में बायोदाई की 'रिपब्लिक ऑफ वियतनाम' सरकार और उत्तर में डॉ. होची-मिन्ह का 'वियतनाम गणतन्त्र' जिसे बीतमिन्ह नाम दिया गया। 30 दिसम्बर, 1949 को बायोदाई ने सैगोन (Saigon) में स्वयं को 'राज्याध्यक्ष' घोषित कर दिया। सैगोन बायोदाई-शासित वियतनाम की राजधानी बनी। डॉ. होची-मिन्ह द्वारा शासित वियतनाम की राजधानी हनोई ही रही।

फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों की कूटनीतिक चालों ने स्पष्टतः वियतनाम में भीषण गृह-युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी क्योंकि एक तरफ तो हनोई सरकार स्वयं को सम्पूर्ण वियतनाम की वैधानिक सरकार कहने लगी और दूसरी ओर सैगोन सरकार सारे वियतनाम की वैधानिक सरकार होने का दावा करने लगी। कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों में लड़ाई शुरू हुई। जो युद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता का होना चाहिए था उसने गृह-युद्ध का स्वरूप ले लिया।

मई, 1954 में डीन बीन फू में फ्रांसीसी सेनाओं की निर्णायक पराजय ने हिन्द-चीन में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद की कमर तोड़ दी और 21 जुलाई को दोनों पक्षों में युद्ध-विराम सन्धि हुई जिसके अनुसार निम्नलिखित बातें स्वीकार हुई—

(i) यह देश दो भागों में विभक्त हो गया—उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। 17वीं अक्षांश रेखा के उत्तर में हनोई नदी से लगता हुआ सारा उत्तर वियतनाम साम्यवादियों के अधिकार में रहा और उसके दक्षिण में दक्षिण वियतनाम गणराज्य की स्थापना हुई।

(ii) दोनों भागों के बीच एक बफर क्षेत्र की भी स्थापना की गई।

(iii) फ्रांसीसी सेना द्वारा सारा वियतनाम खात्ती करने का निर्णय हुआ।

(iv) व्यवस्था की गई कि जुलाई, 1956 में नए निष्पक्ष चुनावों द्वारा दोनों भागों का एकीकरण किया जाएगा।

(v) सन्धि की शर्तों का पालन करने के लिए त्रिसदस्यीय अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग की स्थापना की गई। इसके सदस्य—भारत, कनाडा और पोलैण्ड बनाए गए।

युद्ध-विराम की असफलता और वियतनाम संघर्ष

जेनेवा सम्मेलिते से आशा हुई थी कि वियतनाम में निकट भविष्य में पूर्ण शान्ति स्थापित हो सकेगी और आम चुनाव द्वारा उत्तर व दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हो जाएगा, परन्तु इस प्रकार की कोई आशा फलीभूत नहीं हुई। दोनों पक्षों में कटुता बढ़ती गई। उत्तर की प्रेरणा से दक्षिण वियतनाम में साम्यवादियों ने 1960 में 'राष्ट्रीय मुक्ति सेना' (National Liberation Front) की स्थापना की। इन सैनिकों को सरकारी बयानों में वियत-कांग कहा गया। यह वियत-कांग मगठन सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने लगा। जनवरी, 1962 में अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को प्रचुर आर्थिक और सैनिक सहायता देने की योजनाएँ घोषित की और लगभग एक माह बाद ही वहाँ एक अमेरिकी सैनिक कमान स्थापित कर दी गई। दूसरी ओर रूस और चीन माँग करने लगे कि अमेरिका दक्षिण वियतनाम में युद्ध सामग्री ले जाना बन्द कर दे और वहाँ से अपने सैनिकों को वापस बुला ले। शीतयुद्ध के साथ ही सैनिक उपद्रव भी बढ़ती गई। उत्तर-वियतनाम की ओर से 17वीं अक्षांश रेखा पर दबाव बढ़ता गया। दक्षिण वियतनाम भी अमेरिका की महायत्ना में प्रबल सैन्य-सचय करता गया। अगस्त, 1964 में वियतनाम में घोर भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो गई। 5 अगस्त को अमेरिका ने उत्तर वियतनाम के पनडुब्बी घड्डों तथा तेल-टर्कियों पर भयानक बम-बर्षा की। इसके बाद ही साम्यवादियों ने विशाल पैमाने पर छापामार युद्ध आरम्भ कर दिया और वियत-कांग छापामार दक्षिण-वियतनाम के सैनिक घड्डों को तहम-नहम करने लगे। 7 फरवरी, 1965 में उत्तर-वियतनाम पर अमेरिका के भीषण हवाई हमले शुरू हो गए। संघर्ष का हल निकालने के लिए सम्मेलित-प्रयास चलते रहे। सभी शान्ति-प्रयास व्यर्थ हो गए और मई 1967 की समाप्ति तक उत्तर वियतनाम तथा वियत-कांग सैनिकों और सैनिक ठिकानों पर अमेरिका ने इतने अधिक बम गिराए जितने सम्पूर्ण द्वितीय महायुद्ध के समय जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी नहीं गिराए थे।

वियतनामी संघर्ष की तीव्रता के साथ-साथ समाधान के लिए नूतनीयक गतिविधियाँ भी तेज होनी गईं। अखिर वियतनाम में युद्धबन्दी सम्मेलिते पर 17 जनवरी, 1973 को पेरिस में चार विदेश मन्त्रियों ने औपचारिक रूप में हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षरकर्त्ता पक्ष थे—अमेरिका, दक्षिण वियतनाम, उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम की अस्थायी प्रान्तिशायी सरकार, तथापि युद्ध-विराम के उल्लंघन और सैनिक विवादों का मिलितत्वा बन्द नहीं हुआ। 1975 का नया वर्ष वियतनामी जनता के लिए और भी प्रशुभ सन्देश लेकर आया तथा पुनः भयंकर युद्ध-विस्फोट के लक्षण प्रकट होने लगे। मार्च, 1975 के अन्तिम सप्ताह में ऐसा लगने लगा कि वियतनाम-युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुँच रहा है। 25 अप्रैल,

1975 को दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति पद पर हुआंग वान-नित्त-आगीन हुए और दो दिन बाद ही 30 अप्रैल को संघीत सरकार ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया।

वियतनाम का एकीकरण और उसकी विदेश-नीति

युद्ध की समाप्ति के बाद अनेक छोटे-मोटे प्रश्नों के निपटारे के साथ ही वियतनाम के आर्थिक पुनर्निर्माण और समुत्कीकरण की दिशा में काम किया जाने लगा। अगस्त में, जून 1976 में दोनों वियतनाम समुत्त हो गए। जहाँ तक समुत्त वियतनाम द्वारा अपनाई जाने वाली विदेश-नीति का प्रश्न है उसे भी स्पष्ट कर दिया गया। वियतनामी कामगार पार्टी के प्रथम सचिव ली-दुग्वान ने कहा कि वियतनाम की विदेश-नीति का प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना में अभिवृद्धि करना है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि हम समाजवादी मार्ग का अश्वत्थी तरह से अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। इस एक प्रमुख गुप्त के प्रलावा ली-दुग्वान ने राष्ट्रीय असेम्बली में जिन अन्य मुद्दों पर जोर दिया वे थे— राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखना, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हुए अन्तराष्ट्रीय दायित्वों और समझौतों का पालन करना और साम्राज्यवाद के सभी स्वरूपों का विरोध करना। ली-दुग्वान ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों द्वारा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष का पूर्ण समर्थन करने का आश्वासन दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि उनका देश गुट-निरपेक्ष देशों के प्रयासों में अपना सहयोग देगा ही, साथ ही विश्व की नई अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने की उनकी योजनाओं का भी समर्थन करेगा। सितम्बर, 1977 में वियतनाम को समुत्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो गई।

अरब-इजरायल संघर्ष

(The Arab-Israel Conflict)

अरबवा

पश्चिम एशिया की समस्या

(The Problem of West Asia)

पश्चिम एशिया अरबवा मध्य-पूर्व एशिया की समस्या अरब-इजरायल संघर्ष की समस्या है। यहूदी राज्य इजरायल के निर्माण के बारे में इतना ही जान लेता पर्याप्त है कि द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होते-होते फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों ने अपने-अपने सैनिक संगठनों की स्थापना कर ली और यह प्रदेश यहूद-युद्ध की आग में झूलसने लगा। ब्रिटेन ने 1946 में सारा मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ को सौंप दिया जिसने 1947 के अगस्त में फिलिस्तीन के विभाजन का फैसला किया। अरबों के तीव्र विरोध के बावजूद 14 मई, 1948 को मध्य रात्रि के समय फिलिस्तीन पर ब्रिटिश मैण्डेट (Mandate) की समाप्ति के साथ ही राजधानी तेलअबीब में यहूदियों ने 'इजरायल' राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। वाशिंगटन ने इन

नवीन राज्य की तुरन्त मान्यता प्रदान की और मास्को तथा लन्दन ने भी इसे स्वीकार कर लिया।

अरब-इजरायल समस्या (1948-1967)

अरब राज्य इजरायल के जन्म को बर्दाश्त नहीं कर सके। यहूदी राज्य की स्थापना के दिन ही मिस्र, जोर्डन, ईराक और सीरिया की सेनाएँ फिलिस्तीन में घुस पड़ी और इजरायल पर आक्रमण शुरू हो गया। लगभग 4 करोड़ जनसंख्या और 20 लाख वर्गमील क्षेत्रफल वाले अरब लीग के राज्यों की तुलना में 6½ लाख की आबादी और कुछ हजार वर्गमील के प्रदेश वाले यहूदी राज्य ने अपनी साधन-सम्पन्नता, विदेशी सहायता और उत्कृष्ट रणनीति के बल पर अरबों को पराजित कर दिया। 1949 में सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों से जब युद्ध बन्द हुआ तो इजरायल के पास सयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा तैयार की गई विभाजन-योजना से भी 2 हजार वर्गमील अधिक प्रदेश था। सयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से जो समझौता हुआ उसके अनुसार मिस्र को गाजा-पट्टी मिली जिसमें शरणार्थी अरबों की बसाने की व्यवस्था की गई। जेरुसलम नगर दो हिस्सों में विभक्त हुआ—लगभग एक लाख की आबादी वाला बड़ा हिस्सा यहूदियों के कब्जे में आया और 50 हजार की अरब आबादी वाला हिस्सा जोर्डन के अधिकार में रहा। इस तरह दोनों राज्यों की सीमा इस नगर में होकर रखी गई। इजरायल ने भागे हुए अरबों को वापस लौटने की अनुमति नहीं दी। उसकी नीति के कारण लगभग 10 लाख अरबों को 1953 तक इजरायली प्रदेश छोड़कर अन्य अरब देशों में शरणार्थी बन कर रहना पड़ा और बदले में यूरोप, अफ्रीका एवं मध्यपूर्व के विभिन्न देशों से 6 लाख यहूदी आकर वहाँ बस गए। जहाँ 1948 में इजरायल राज्य में 13½ लाख अरब और 6½ लाख यहूदी थे वहाँ 1958 में लगभग 20 लाख की कुल जनसंख्या में यहूदियों की संख्या लगभग 17 लाख हो गई।

इजरायल राज्य की स्थापना और फिर युद्ध में इजरायल के हाथों पराजय ने सम्पूर्ण अरब जगत् में स्थायी रूप से इजरायल-विरोधी अग्नि प्रज्वलित कर दी। प्रतिशोध की आग में जलते हुए अरब राज्यों ने इजरायल को न केवल आर्थिक व राजनीतिक रूप से लगभग घेराने की कोशिश कर दिया बल्कि इजरायली बन्दरगाहों से सामान लाने तथा वहाँ पहुँचने वाले जहाजों के लिए स्वेज नहर का सम्मान भी बन्द कर दिया। इजरायल ने यूरोपीय देशों से व्यापारिक समझौते बन्द, अमेरिका तथा वहाँ के सम्पन्न यहूदियों से विपुल आर्थिक सहायता प्राप्त करके और सबसे बड़कर अपने अदम्य साहस के बल पर अरबों की चुनौती पर विजय पा ली। देखते ही देखते इजरायल मध्य-पूर्व का सबसे विकसित और सम्पन्न देश बनने की दिशा में अग्रसर हुआ।

सीमावर्ती अरब राज्यों और इजरायल के बीच छुट-पुट सैनिक झड़पें चलती रही। तनाव घटना-बढ़ता रहा और कभी-कभी तो पूर्ण युद्ध के खतरे भी पैदा हुए। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद 29 दिसम्बर को तब रिफोर्टा सिविल

उत्पन्न हुई जब इजरायली सेनाओं ने मिनार्ड प्रायद्वीप में मिस्र गोर्खों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का स्पष्ट उद्देश्य फेदीमीन अड्डों को नष्ट करना था क्योंकि इन अड्डों से ही भूतकाल में इजरायल पर अधिनाश आक्रमण किए गए थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने भण्डों में मध्यस्थ बनने की माँग की और सुरक्षा-परिपद् से माँग की कि मिस्र को रैनिक हस्तक्षेप की धमकी दी जाए, लेकिन ये सभी बातें दिखावटी थी और परिपद् के नियंत्रण का इन्तजार न कर 31 अक्टूबर, 1956 को दोनों राष्ट्रों ने पोर्टसईड पर आक्रमण कर दिया ताकि स्वेज प्रदेश उनके अधिनार में आ जाए। इस तरह मिस्र को अब अकेले ही तीन शक्तियों से जूझना पड़ा—मिनार्ड में इजरायल से और स्वेज-क्षेत्र में ब्रिटेन व फ्रांस से। पाँच दिनों की लड़ाई के बाद लगभग सम्पूर्ण मिनार्ड प्रायद्वीप पर इजरायल का नियन्त्रण स्थापित हो गया। आखिर सोवियत रुम की गम्भीर चेतावनी के फलस्वरूप 6-7 नवम्बर को मध्य-रात्रि से ब्रिटिश फ्रांसीसी सेनाओं ने युद्धबन्दी की घोषणा कर दी। 6 नवम्बर को ही महासभा द्वारा एशिया अफ्रीका के देशों का यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजरायली सेनाएँ मिस्र की भूमि से हट जाएँ तथा स्वेज नहर के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस नियुक्त की जाए। 15 नवम्बर को मयुक्त राष्ट्र गधीय आपात्कासीन सेना का पहला दस्ता मिस्र पहुँच गया। आक्रमणकारी सेनाओं द्वारा अपनी सेनाएँ हटाने में ढील करने पर महासभा द्वारा पुनः प्रस्ताव पारित किए गए और आखिर 22 दिसम्बर, 1956 को ब्रिटेन तथा फ्रांस ने और 7 मार्च, 1957 को इजरायल ने अपनी सेनाएँ हटानी। इजरायल ने कुछ शर्तों के साथ सेनाएँ हटाना स्वीकार किया। प्रमुख शर्तें ये थी कि अकबा की खाड़ी तथा तिरान जलडमरूमध्य में इजरायल महिन सब देशों के लिए नौ-चालन की पूरी स्वतन्त्रता होगी और मयुक्त राष्ट्रसंघ उस समय तक गाजापट्टी पर अपना प्रशासन रखेगा जब तक कि इसके भविष्य के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो जाता।

संरक्षक संघर्षों की समाप्ति के उपरान्त भी तनाव जारी रहा और एक-एक कर छोटी-मोटी रैनिक झड़पें भी होनी रहीं। 1962 के अन्तिम चरण में जोर्डन नदी के पानी का विवाद तूल पकड़ गया और ऐरिक जॉस्टन की योजना के अनुसार यह निश्चित किया गया कि इसके जल का 67% भाग अरब-राज्य और 33% भाग इजरायल अपने उपयोग में लाए। इजरायल ने अपने हिस्से के जल का उपयोग करने के लिए योजना आरम्भ करदी। अरब-राष्ट्र इस स्थिति को सहन करने की मानसिक अवस्था में नहीं थे, अतः 13 अरब-राज्यों ने जनवरी, 1964 में काहिरा में एक शिखर-सम्मेलन आयोजित किया जिसमें मुख्यतः तीन विषयों पर विचार हुआ—(1) जोर्डन नदी के पानी की समस्या, (2) अरब-राज्यों की संयुक्त सेना का निर्माण; एवं (3) सभी अरब-राष्ट्रों द्वारा मिलकर इजरायल को नष्ट करना। सम्मेलन में स्पष्ट हो गया कि अरब-राष्ट्रों में अनेक विषयों पर प्रबल मतभेद विद्यमान थे और इजरायल के विनाश अथवा विरोध के विषय में सब राष्ट्रों में सहमति नहीं थी।

आपसी मतभेदों के बावजूद अरब-राष्ट्रों में इजरायल के प्रति विरोध की भावना ही बलवती रही और एक नए अरब-इजरायल सवर्ण की भूमिका बनती गई। मई, 1967 में संयुक्त अरब-गणराज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति नासिर ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-सेनाओं को सीमाओं से हटा लेने की माँग की। महासचिव ऊ-थांट ने चेतावनी भरे शब्दों में बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय सेनाओं के हट जाने से दोनों पक्षों की फौजें एक-दूसरे के आमने-सामने हो जाएँगी और जो शान्ति बनी हुई है वह नष्ट हो जाएगी लेकिन नासिर के आग्रह के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं का हट जाना पड़ा। दोनों पक्षों में छोटी-मोटी सैनिक मुठभेड़ें होने लगीं और साथ ही अमेरिका तथा रूस दोनों के युद्धपोत भी भूमध्यसागर में मोर्चों पर पहुँच गए। इस प्रकार पश्चिमी एशिया के संकट ने दो महाशक्तियों के टकराने की स्थिति पैदा कर दी।

सोमवार, 5 जून, 1967 को भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 11.30 बजे इजरायल ने संयुक्त अरब गणराज्य की राजधानी काहिरा पर अचानक भीषण हवाई हमला कर दिया और एक ही घंटे में मिस्र के अधिकांश विमान घराशायी हो गए। अरबों इजरायल ने सभी मोर्चों पर अरब-राष्ट्रों की संयुक्त शक्ति पर नहर ढा दिया और 6 दिनों में ही निर्णायक विजय प्राप्त करली। 8 जून तक इजरायली फौजें मिनार्ई प्रायद्वीप को पार कर स्वेज नहर के पूर्वी कोने पर जा पहुँची। इसी बीच 7 जून को सुरक्षा-परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा माँग की कि युद्धगत और सभी देशों के 8 बजे से (ग्रिनविच समय) युद्धबन्दी कर दें। परिषद् का यह प्रादेशात्मक प्रस्ताव था। संयुक्त अरब-गणराज्य ने जिसकी कमर बुरी तरह टूट चुकी थी तुर्क ही युद्ध-विराम स्वीकार कर लिया। 8 जून को इजरायल और संयुक्त अरब-गणराज्य के बीच युद्ध बन्द हो गया। सीरिया और इजरायल में नश्वर जारी रहा और 9-10 जून को सुरक्षा-परिषद् को पुनः आदेश देना पड़ा कि दो घण्टे में युद्ध बन्द कर दिया जाए। इस समय तक इजरायल का सामरिक उद्देश्य पूरा हो चुका था और सीरिया की सामरिक क्षमता समाप्त हो चुकी थी, अतः 10 जून को दोनों पक्षों में लड़ाई पूरी तरह बन्द हो गई। संयुक्त अरब-गणराज्य ने अमेरिका और ब्रिटेन पर आरोप लगाया कि उनके विमानों ने इजरायल की सहायता देकर युद्ध में भाग लिया था। अरब राज्यों ने दोनों देशों से अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिए और यह आदेश भी दिया कि सभी अमेरिकी तथा ब्रिटिश नागरिक अपने देश लौट जाएँ।

अरब-इजरायल तनाव और शान्ति प्रयास (जुलाई, 1967-1972)

युद्ध की समाप्ति के बाद शान्ति-गमभीने के कूटनीतिक गवर्ण की शुरुआत हो गई। इजरायल ने विजित क्षेत्रों से हटने के लिए दृढ़तापूर्वक इस्तेमाल कर दिया जबकि राष्ट्रपति नासिर ने घोषणा की कि उन्हें अरब-भूमि पर से हटना पड़ेगा। दोनों पक्षों में छोटे-मोटे घातमलों-प्रत्याघातों का मिश्रण भी चलता रहा। जून, 1969 में अरब-देशों में तब बहुत ही उत्तेजना फैल गई जब इजरायल ने जेरुसलम

को विविध इजरायल राज्य में मिलाने की घोषणा कर दो। मुरझा-परिषद् में पाकिस्तान, जाम्बिया, सेनेगल आदि ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इजरायल की निन्दा करते हुए प्रादेश दिया गया कि वह जेहूदसलम को मिलाने की घोषणा वापस ले। प्रस्ताव हो गया, लेकिन इजरायल ने उसे मानने से इन्कार कर दिया।

सितम्बर, 1969 में मोरक्को की राजधानी रबात में इस्लामी देशों के शिखर-सम्मेलन में मुस्लिम देशों की कूट पुन उजागर हो गई और अरब-राष्ट्रों की यह इच्छा सफल नहीं हो सकी कि सभी मुस्लिम देश इजरायल से सम्बन्ध-विच्छेद कर ले। एक प्रकार से यह इजरायल की ही एक बहुत बड़ी राजनीतिक विजय थी। जुलाई, 1970 में इजरायल की ओर से प्रत्यक्ष-वार्ता का प्रस्ताव रखा गया और लगभग इसी समय अमेरिका ने प्रस्ताव दिया कि 90 दिनों तक कोई भी पक्ष आक्रमण न करे तथा इस शर्त पर शान्ति-वार्ता शुरू हो कि इजरायल विजित क्षेत्रों को सौंपी कर दे तथा अरब देश इजरायल की सीमा में इजरायल की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें। प्रस्ताव दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया और 7 अगस्त से पूरी तरह युद्ध-विराम लागू हो गया। सितम्बर, 1970 में नागिर की मृत्यु से शान्ति-वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया। फरवरी, 1971 में संयुक्तराष्ट्र संघ के अध्यक्ष डॉ गन्तार जारिग ने संयुक्त-अरब-गणराज्य तथा इजरायल के सामने अपना निम्नलिखित पंचमूत्री प्रस्ताव पेश किया—

- (1) दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति समाप्त की जाए।
- (2) दोनों एक-दूसरे की प्रादेशिक स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता को मान्यता दे।
- (3) मान्यता प्राप्त सीमाओं और मुरक्षा के अन्तर्गत दोनों शान्तिपूर्वक रहने का एक समझौता करें।
- (4) दोनों अपनी-अपनी सीमाओं और प्रदेशों से एक-दूसरे के विरुद्ध बल-प्रयोग बंधवा इस प्रकार की धमकी का सहारा न लें।
- (5) एक-दूसरे के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न करें।

डॉ. जारिग ने यह पुराना सुझाव भी दोहराया कि इजरायल को अपनी सेनाएँ उस स्थान तक पीछे हटा लेनी चाहिए जो संयुक्त-अरब-गणराज्य तथा इजरायल के बीच की परम्परागत सीमा है। युद्ध-विराम की अवधि और भी बढ़ा दी गई।

अप्रैल, 1971 के आसपास इजरायल ने स्वेज नहर पुन. खोले जाने के सम्बन्ध में अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा कि वह स्वेज के पूर्वी तट से अपनी सेनाएँ हटाने के लिए तैयार है बशर्ते कि, (1) संयुक्त-अरब-गणराज्य घोषणा करे कि इजरायल के प्रति उसका आचामक रवैया खत्म हो चुका है, (2) स्वेज-तट से इजरायली सेना की वापसी के समय यदि संयुक्त-अरब गणराज्य या सोवियत संघ बलपूर्वक नहर पार करने का प्रयत्न करे तो उन्हें रोकने के लिए ठोस आश्वासनों और प्रतिवन्दों की अग्रिम व्याख्या की जाए, और (3) जब तक अन्तिम समझौता नहीं हो जाता तब तक इजरायल अविच्छिन्न सिनई रेगिस्तान से वापसी के बारे में किसी

प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं करेगा। इजरायल के प्रस्ताव अरब-पक्ष को मान्य नहीं हो सकते थे।

पश्चिमी एशिया का संकट शान्ति-प्रयास और युद्ध की आशंकाओं के बीच झूलता रहा। 27 मई, 1971 को मित्र और रुस के बीच 15 वर्षीय मैत्री-सन्धि हो गई। रुस ने अधिकाधिक सैनिक मदद का आश्वासन दिया और इजरायल की पीठ पर पूरी तरह अमेरिका था। जो भी प्रस्ताव-प्रतिप्रस्ताव सामने आए उन्हें किसी भी पक्ष ने स्वीकार नहीं किया। इसी समय मित्र और रुस के सम्बन्धी में कुछ तनाव पैदा हो गया तथा जुलाई, 1972 में राष्ट्रपति सादात ने रुसी सैनिक विशेषज्ञों को मित्र छोड़ने का आदेश देकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् को स्तब्ध कर दिया। सितम्बर, 1972 में 'यूनिक्स हत्याकांड' के फलस्वरूप इजरायल-अरब तनाव और भी बढ़ गया। बदले की कार्यवाही कर इजरायल ने सेबनान के छापामार ठिकानों पर हवाई आक्रमण किया। बहुत से छापामार ठिकानों को नष्ट करने के बाद इजरायल शान्त हुआ और उसने कहा कि सेबनान की भूमि पर या नागर्ग्वि ठिकानों पर आक्रमण करने का उनका कोई इरादा नहीं है।

अरब-इजरायल संघर्ष (1973-1980)

1973 में सजेत स्पष्ट हो गए कि स्वेज नहर का युद्ध-विराम अधिक समय तक नहीं चल सकेगा। सामान्यतः दोनों पक्ष अपनी-अपनी शर्तों पर खड़े रहे। इजरायल यह माँग करता रहा कि—

1. अरब-राष्ट्र इजरायल को राजनीतिक मान्यता दें।
2. स्वेज नहर और अकबा की खाड़ी में इजरायल को उसी तरह जहाजरानी के अधिकार मिलें जैसे दूसरे देशों को प्राप्त हैं।
3. जेरुसलम इजरायल के अधिकार में रहे।
4. जोर्डन नदी के पश्चिम की तरफ का क्षेत्र फिलिस्तीनी विस्थापितों के लिए अलग कर दिया जाए।
5. सीरियाई सीमान्त का वह पहाड़ी क्षेत्र जहाँ से इजरायल के विंग्ड छेड़छाड़ की जाती है, इजरायल के ही अधिकार में रहे।
6. इजरायल से छेड़छाड़ न करने का विश्वसनीय आश्वासन दिया जाए।

स्पष्ट है कि इजरायल को माँगें बहुत अधिक सौदेबाजी की थी जो अरब-राष्ट्रों को मान्य नहीं हो सकती थी। मयुक्त अरब-मसराज्य और उसके साथ ही अरब राष्ट्रों की माँग थी कि—

1. वे एक इंच अरब-भूमि भी हाथ में नहीं जाने देंगे।
2. अपनी प्रभुता में वे कभी कोई हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे।
3. इजरायल को युद्ध द्वारा हथियवाई गई जमीन वा साथ नहीं उठाने देंगे।
4. क्षेत्र में इजरायली जहाजरानी तभी हो मनेगी जब इजरायल जीने हुए क्षेत्र को खाली कर दे।

अरब-राष्ट्रों और इजरायल में तनाव बढ़ता गया और गतिवार, 6 अक्टूबर, 1973 को अचानक ही मित्र की सेनाओं ने इजरायल अधिकृत अपने प्रदेश को मुक्त कराने के लिए युद्ध छेड़ दिया। 6 वर्ष पहले जून, 1967 के 6 दिवसीय अरब-इजरायल युद्ध में इजरायल ने पहल की थी और अरब-राष्ट्रों को बुरी तरह पराजित किया था। इस बार पहल मित्र और सीरिया ने की किन्तु वे इजरायल की तरह युद्ध का भरपूर लाभ नहीं उठा पाए। युद्ध 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 1973 तक चला और तब दोनों पक्षों में युद्ध-विराम हो गया। दोनों पक्षों को 1967 की सट्टाई की तुलना में कहीं अधिक क्षति हुई, तथापि यह मित्र हो गया कि इजरायली सेना सर्वथा अपराजेय नहीं है और अरबों में भारी युद्ध क्षमता है। युद्ध-विराम सुरक्षा-परिषद् के आदेश पर हुआ। युद्ध-विराम के समय निम्नलिखित लगभग यह थी कि इजरायल स्वेज नहर के पश्चिमी तट पर और सीरिया में सामा के पास तक मोर्चे खींचकर नहीं जमीन हथियाने में सफल रहा। इसके विपरीत मित्र ने स्वेज पार 305 मील की लम्बी पट्टी पर कब्जा कर लिया और सीरिया ने गोलन पहाड़ी क्षेत्र के कुछ भाग पर।

सुरक्षा परिषद् ने युद्ध-विराम सम्बन्धी जो प्रस्ताव पारित किया, उसमें आग्रह किया गया कि सशस्त्र सन्धि पक्ष सैनिक गतिविधियाँ तत्काल रोक दें और स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए सम्बद्ध पक्षों में समुचित तत्वावधान में बानचीन हो। सशस्त्र देशों में सीरिया ने युद्ध-विराम प्रस्ताव स्वीकार करने में काफी देर लगाई।

युद्ध-विराम के बाद मित्र और इजरायल समझौता बार्ता चालू रहे। आंशिक समझौते हुए भी, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान एक विरुद्ध प्रश्नचिह्न हो बना रहा। क्रिस्फरवाइडरक परिस्थितियाँ बनीं, लेकिन दोनों पक्षों के समय के कारण सघर्ष नहीं छिड़ा। राष्ट्रपति सादान यह मानकर चलें कि इजरायल अपनी घरेलू स्थितियों के कारण शान्ति-स्थापना का इच्छुक है और यदि कटु सल न अपनाया जाए तो दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक समझौता हो सकता है।

अरब राष्ट्रों की अप्रमत्तता की परवाह न करते हुए मित्र के राष्ट्रपति जनवर सादान ने इजरायल जाने का फैसला किया। 29 वर्ष की घोर शत्रुता और युद्ध को ताक पर रखकर 10 नवम्बर, 1977 को उन्होंने इजरायली सदन से पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापित करने में सहायता का अनुरोध किया। सादान के बाद बेगिन ने मित्र में इस्राइलिया आकर सादान से बानचीन की। एक दूसरे के प्रति समझौतावादी भावना का विकास होना गया, लेकिन माभेय सुलभ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर दोनों पक्षों में समझौते के लिए विशेष प्रयत्न करते रहे और अन्त में सितम्बर, 1978 में अमेरिका में कैम्प डेविड में पश्चिम-एशिया समस्या पर कार्टर-सादान-बेगिन शिखर बार्ता हुई। 13 दिनों की बानचीन अनेक बार गानुका दौर से गुजरी और अन्त में एक ऐतिहासिक समझौते के साथ समाप्त हुई।

सितम्बर की मित्र-इजरायल शान्ति-सन्धि के इस दस्तावेज में इजरायल ने कहा कि (1) वह समूचे मिनाई में मित्र की प्रमुखता को फिर स्वीकार करते हुए वहाँ से अपना हवाई अड्डा समाप्त कर देगा, (2) इजरायली सेनाएँ शान्ति-सन्धि पर

हस्ताक्षर होने के बाद (इजरायली ससद् की स्वीकृति के बाद), तीन महीने से लेकर 9 महीने तक की अवधि में हट जाएगी, (3) तत्पश्चात् दोनों पक्षों के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो जाएंगे, (4) दस्तावेज में स्पष्ट कर दिया गया कि पाँच वर्ष के सन्तान्त्रिक काल में इजरायल जोर्डन के पश्चिम तक और गाजा पर से अपना सैनिक नियन्त्रण पूरी तरह समाप्त कर देगा, इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन और पूर्ण-स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन सुरक्षा-सम्बन्धी कुछ कारणों से इजरायल कुछ इलाकों में अपने सैनिक रखेगा, (5) पश्चिमी तट का मामला तय करने के लिए जोर्डन को वातचीत में आमन्त्रित किया जाएगा और उसे इजरायल के साथ शान्ति-वार्ता के लिए भी कहा जाएगा।

कैम्प डेविड वार्ता के परिणाम पर मित्र और इजरायल में तथा अरब देशों में तीव्र प्रतिक्रियाएँ हुईं। अरब जगत में सीरिया ने कैम्प डेविड समझौते की कड़ी आलोचना की और कहा कि अरब हितों का बलिदान कर दिया गया है। कैम्प डेविड समझौते की अल्जीरिया, लीबिया, सीरिया, दक्षिणी यमन, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, सऊदी अरब इन सभी अरब राष्ट्रों ने विरोध किया और सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की इच्छा प्रकट की। कैम्प डेविड समझौते के सन्दर्भ में मित्र और इजरायल के प्रतिनिधियों में वार्ता का दूसरा दौर 12 से 22 दिसम्बर 1978 तक चला और समझौते की व्याख्या को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद पैदा हो गए।

राष्ट्रपति कार्टर की प्रतिष्ठा बाब पर लग गई और आखिर मार्च, 1979 के प्रारम्भ में यह घोषणा हो गई कि कैम्प डेविड में मित्र और इजरायली नेताओं में शान्ति-सन्धि के लिए समझौते का जो ढाँचा बनाया था वह जीवन्त ही अस्तित्व में आ जाएगा। ऐसा ही हुआ और 26 मार्च, 1979 को वाशिंगटन में राष्ट्रपति कार्टर के हस्ताक्षर सहित मित्र और इजरायल में शान्ति-सन्धि सम्पन्न हो गई। सन्धि पर सादर, बेगिन और कार्टर के हस्ताक्षर हुए। इस शान्ति-सन्धि पर अरब देशों ने तुरन्त विरोध किया और 1 अप्रैल, 1979 को अरब संघ के 16 सदस्यों ने मित्र का बहिष्कार करने और आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के पहले कदम के तौर पर बाहिर स्थित राजदूतों को स्वदेश लौट आने का आदेश दिया।

मित्र के प्रधानमंत्री डॉ. मुस्तफा सलील ने बताया कि सन्धि के लागू हो जाने से पहले नौ महीनों में इजरायल मिनार्ई का 75% इलाका उसे लौटा देगा। इसके एक क्षेत्र में इजरायल की पोलो सेना रहेगी। एक-तिहाई क्षेत्र में संयुक्तराष्ट्र सैनिकें रखी जाएंगी। मिनार्ई का पूरा क्षेत्र दो से तीन माल के भीतर मित्र को सौंप दिया जाएगा। सन्धि की पुष्टि हो जाने के नौ महीने के भीतर मित्र और इजरायल राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करेंगे। मित्र अपना इलाका तत्पश्चात् में लौटेगा, परन्तु नम में नहीं। फिलिस्तीनी राजनीतिक बन्धियों को रिहा किया जाएगा। सन्धि पर हस्ताक्षर होने के एक महीने के बाद पश्चिमी तटारे और गाजा-पट्टी में फिलिस्तीनी शरणार्थी लौट जाएँगे। यह संक्रमणकाल पाँच वर्ष तक रहेगा। उसके

बाद फिलिस्तीनियों को अपने भाग्य का फैसला करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर होने के दम महीने के बाद चुनाव होंगे।

मार्च, 1979 के कैम्प डेविड सम्मेलन का भरख और इजरायल के उपवादी तरफों ने तीव्र विरोध किया। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेताओं ने माँग की कि फिलिस्तीनियों को सभी समस्याओं पर विचार-विमर्श होना चाहिए। जून, 1980 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने बेनिन में पश्चिम एशिया में पूर्ण शान्ति के लिए एक नई नीति निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा तथापि मिस्र के राष्ट्रपति सादान ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी समझौता कैम्प डेविड सम्मेलन के अन्तर्गत ही दूँदा जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत व्यापक सम्मेलन है जो अब केवल इजरायल और मिस्र तक ही सीमित नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि कैम्प डेविड सम्मेलन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए यूरोपीय देशों को अमेरिका के साथ-साथ मिस्र और इजरायल की सहमति लेनी होगी। लगभग इसी समय संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक विशेष अधिवेशन में इजरायल से सभी विजित अरब क्षेत्रों से हटने का आग्रह किया किन्तु इन प्रस्ताव का इजरायल पर कोई असर नहीं हुआ। यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के प्रश्न पर सभी प्रमुख अरब देशों ने रखा था और इसमें महासचिव डॉ. कुबे यान्दहीन से अनुरोध किया गया था कि अरब विजित प्रदेशों में इजरायली सेनाओं को हटने की मारी कार्यवाही की देर-भात के लिए वह संयुक्तराष्ट्र दल तैनात करें। प्रस्ताव में कहा गया था कि संयुक्तराष्ट्र सत्र इजरायल से वहे वह 15 नवम्बर, 1980 तक सभी अरब विजित प्रदेश खाली कर दे। भारत सहित अनेक देशों ने माँग की थी कि फिलिस्तीनियों को अपना राज्य बनाने का अधिकार देने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री पी. वी. नरसिंहराव का कहना था कि यरूशलम गृहित सभी विजित अरब प्रदेशों से हटने के लिए इजरायल को मजबूर करने का समय आ गया है। भारतीय विदेश मंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर खेद व्यक्त किया कि सुरक्षा परिषद् इजरायल के प्रति कड़ा खंबा नहीं अपना सकी है, वह इजरायल को अपनी बात मनवाने से मजबूर करने के लिए कतराती रही है और यही कारण है कि इजरायल फिलिस्तीनी और अरबों को दवाने में बराबर कामयाब रहा है। उपरोक्त प्रस्ताव में कहा गया था कि इजरायल द्वारा खाली किया गया इलाका फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को सौंप दिया जाए ताकि फिलिस्तीनियों के अपना अलग देश बनाने के अधिकार को मान्यता मिले। कहा गया कि गाजा-नद्दी और जोर्डन नदी का पश्चिमी किनारा फिलिस्तीनी क्षेत्र माना जाएगा। इजरायल ने संयुक्तराष्ट्र सत्र की पूर्णतया अवहेलना करते हुए यरूशलम को अपनी राजधानी बनाने का अन्तिम निर्णय कर लिया।

अरब-इजरायल विवाद 1981-1982

अरबों और इजरायल के बीच विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सका और समय-समय पर रिश्तेति बिरफोडक बनती रही। मई, 1981 में लेवतान में सीरिया और इजरायल के टकराव से समूचे पश्चिम एशिया में पुनः एक बड़े युद्ध

का खतरा पैदा हो गया। महाशक्तियों के हस्तक्षेप का खतरा पैदा हो गया तथापि स्थिति सम्भल गई। जून, 1981 में इजरायल ने आकस्मिक हवाई आक्रमण में ईराक के परमाणु सयन्त्र नष्ट करके अपनी उग्रवादी और आक्रामक नीति का परिचय दिया और स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी अरब राष्ट्र को परमाणु शक्ति सम्पन्न न बनने देने के लिए कटिबद्ध है।

सऊदी अरब की आठ-सूत्री शान्ति योजना (अगस्त 1981)—पश्चिमेशिया की समस्या के समाधान के लिए सऊदी अरब के युवराज फाहद ने 8 अगस्त, 1981 को एक आठ-सूत्री शान्ति योजना प्रस्तावित की—

- (1) यरूशलम के अरब क्षेत्र सहित 1967 के सभी अरब विजित प्रदेशों में इजरायल की वापसी।
- (2) 1967 से अरब क्षेत्रों में इजरायल ने जितनी भी वस्तियाँ बसायी हैं उन सभी का वहाँ से खालना।
- (3) पवित्र स्थानों में सभी जगह पूजा और धर्म सम्बन्धी सभी बायों के पालन की स्वतन्त्रता।
- (4) फिलीस्तीनियों के स्वदेश वापसी के अधिकार को मान्यता और जाँ नही सौटना चाहते उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था।
- (5) पश्चिमी तट और गाजा पट्टी पर सत्रात्मिकाल की अधि में मयुक्त-राष्ट्र का नियन्त्रण।
- (6) फिलीस्तीनियों के स्वतन्त्र राज्य बनाने के अधिकार को मान्यता और इस राज्य की राजधानी यरूशलम होने पर सहमति।
- (7) इस क्षेत्र के देशों को अपनी-अपनी सीमाओं में शान्ति और सुरक्षा से रहने के अधिकार को मान्यता।
- (8) मयुक्तराष्ट्र द्वारा इन मुद्दों को लागू करने की गारण्टी या फिर विश्व सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा इन मुद्दों को लागू करने का आश्वासन।

सऊदी अरब की शान्ति योजना में पश्चिम एशिया की समस्या को एक नया ही मोड़ दे दिया। इस योजना में फिलीस्तीनियों का एक नया राज्य बनाने की बात तो है ही, साथ ही इजरायल के सभी अरब विजित प्रदेशों से हटने की भी व्यवस्था है। अपनी इस योजना को स्पष्ट करते हुए युवराज फाहद का कहना है समस्या के समाधान में विश्व की दोनों महान् शक्तियों—मोवियन मश और अमेरिका—की महत्वपूर्ण भूमिका है। सऊदी अरब योजना के दो उद्देश्य स्पष्ट नजर आते हैं। कॅम्प डेविड समझौता अपने आप ही खत्म हो जाए जिसने पूरे अरब जगत् को शस्त्रों में बाँट दिया है, दूसरे इजरायल के साथ भगड़े को लेकर पश्चिमेशिया की समस्या का एक ऐसा समाधान निकाले जिस पर सभी अरब देश सहमत हों। पर साथ ही यह भी निश्चिन है कि इस योजना का अमेरिका और इजरायल दोनों ही

अन्तकाल तक लटकाए रखना चाहेंगे। खाड़ी देशों ने सऊदी अरब की शान्ति योजना को अपना समर्थन दिया। छ. खाड़ी देशों के रियाद शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया था कि सऊदी अरब अपनी योजना को नवम्बर, 1981 में होने वाली अरब मध की बैठक में स्वीकृति के लिए पेश करे। खाड़ी शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतार और बहरीन के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया था। शिखर सम्मेलन का विचार था कि खाड़ी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा विशेष कर विदेशी सैनिक ब्रिगो से प्रलग रखा जाना चाहिए। सम्मेलन के अनुसार सऊदी अरब योजना के आधार पर ही अरब देश किलीस्तीनी समस्या पर समान रवैया अपना सकेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि खाड़ी देशों के इस शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति में मित्र का कही जिक्र नहीं किया गया। बस इतना ही कहा गया कि खाड़ी देशों को आशा है कि मित्र अरब खेम में फिर लौट आएगा। इजरायल के साथ 1979 की शान्ति सन्धि के कारण मित्र को 22 सदस्यों के अरब मध से हटा दिया गया था।

कुछ तटस्थ यूरोपीय और अरब देश भी सऊदी अरब की योजना का समर्थन कर रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि सऊदी अरब की शान्ति योजना इजरायल के पश्चिमी यूरोपीय सहयोगी देशों को भी स्वीकार्य हो। अमेरिका द्वारा इस योजना को मान लेने पर वह इजरायल को भी सहमत करा पाएगा, इसमें सन्देह है। लेकिन बेगिन, इजरायली प्रधानमन्त्री ने अमेरिका द्वारा सऊदी अरब की आठ-सूत्री इस योजना को समर्थन देने पर सख्त नाराजगी प्रकट की थी। उनका कहना था कि इस योजना में अपनी-अपनी सीमाओं में सुरक्षित रहने का अधिकार रखने वाले देशों में इजरायल का वही नाम ही नहीं है।

मित्र के राष्ट्रपति हुस्नीमुबारक ने सऊदी अरब की योजना को समर्थन दिया, और इसे कैम्प डेविड समझौते का, एक विकल्प बताया।

अमेरिका ने सऊदी अरब योजना को कैम्प का विकल्प नहीं माना। जोर्डन के शाह हुसैन की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रीगन ने सऊदी अरब योजना को लेकर शाह हुसैन से अपने मतभेद व्यक्त किए थे। कहा जाता है कि राष्ट्रपति रीगन ने शाह हुसैन से स्पष्ट कह दिया था कि वह किसी भी हालत में कैम्प डेविड समझौते की प्रक्रिया में रुकावट नहीं चाहते। यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच भी इस योजना पर मतभेद नजर आए।

सितम्बर 1981 से मार्च 1982 तक की घटनाएँ—16 सितम्बर को अमेरिका और इजरायल के बीच एक नए मैत्री और सैनिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 6 अक्टूबर, 1981 को मित्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या से पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापना की प्रक्रिया को गहरा आघात लगा तथापि उनके उत्तराधिकारी हुस्नी मुबारक ने स्पष्ट कर दिया कि ये सादात की नीति पर चलते रहेंगे। 1 नवम्बर, 1981 को अमेरिका ने पश्चिमेशिया में शान्ति स्थापना सम्बन्धी सऊदी अरब के शान्ति प्रस्ताव से सहमति प्रगट की, लेकिन इजरायल उसे मानने से इन्कार

कर दिया। मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने भी 8 नवम्बर, 1981 को सऊदी अरब की आठ-सूत्री शान्ति योजना का अनुमोदन कर दिया लेकिन इजरायल की सहमति के बिना यह शान्ति योजना कोई मायने नहीं रखती थी। 15 दिसम्बर, 1981 को इजरायल ने सीरिया की गोलन पहाड़ियों पर विधिवत् कब्जा करने का फैसला करके अरब-इजरायल तनाव को पुनः बढ़ा दिया। 17 दिसम्बर को सुरक्षा परिषद् ने इजरायल के इस फैसले की भर्त्सना की, लेकिन 18 दिसम्बर को इजरायल ने सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 21 जनवरी, 1982 को अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए इजरायल पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग किया। संयुक्तराष्ट्र में 30 जनवरी, 1982 को सीरिया ने जोरदार माँग की कि इजरायल के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाए जाएँ। इसके पूर्व दिसम्बर, 1981 के महासभा के एक अधिवेशन में भारत और 15 अन्य देशों द्वारा रखा गया इजरायल विरोधी यह प्रस्ताव पारित हो चुका था कि गोलन पहाड़ियों को नाजायज तौर पर इजरायल में शामिल करने की सजा के तौर पर इजरायल का हुक्का-पानी बन्द कर दिया जाए। प्रस्ताव में अमेरिका की भी निन्दा की गई कि उसने सुरक्षा परिषद् में निषेधाधिकार का प्रयोग करके बहुत गलत काम किया है। 1 फरवरी, 1982 को सीरिया द्वारा पश्चिम एशिया के बारे में एक तीन-सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो कि नागजी बन कर रह गया। 6 फरवरी, 1982 को इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने विरुद्ध प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रस्ताव को अवैध ठहराते हुए अस्वीकार कर दिया।

पश्चिम एशिया अज्ञान्त है और अरब-इजरायल विवाद कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर सकता है तथापि यह स्पष्ट है कि अरब देशों और इजरायल के बीच स्थायी शान्ति के आधार अब जितने प्रबल हैं उतने पहले कभी नहीं थे क्योंकि अरब देश यह समझ चुके हैं कि उन्हें देर-सवेर इजरायल के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। यदि महाशक्तियाँ एक दूसरे पक्ष को उकसावे नहीं और शान्ति स्थापना की दिशा में ईमानदारी से प्रयत्न करें तो शान्ति की समस्या हल हो सकती है। दुर्भाग्यवश अमेरिका के रीगन प्रशासन ने पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में रचनात्मक रवैया नहीं अपनाया है, वह इस क्षेत्र को सघर्ष के मार्ग पर ही ले जा रहा है। अरब देशों के भीतर भी विघटन की प्रवृत्तियाँ कम नहीं हुई हैं। इन परिस्थितियों में शान्ति के साथ-साथ सघर्ष के बने रहने की भी अधिक सम्भावना है।

ईराक-ईरान संघर्ष (Iraq-Iran Conflict)

ईराक-ईरान संघर्ष भी पश्चिम एशिया की एक गम्भीर समस्या है। इन दोनों देशों के बीच तनातनी काफी लम्बे अरसे से चली आ रही थी और मितम्बर, 1980 के प्रारम्भिक सप्ताह में छुट-पुट सैनिक झड़पें भी हुई थी लेकिन 22 मितम्बर, 1980 को ईरानी बमबर्षा द्वारा तेहरान महिन अनेक ईरानी हवाई अड्डों और मैनव डिपानों पर बमबारी के साथ दोनों देश पूरे युद्ध पर उतर आए। राष्ट्रमण की सुरक्षा

परिपद् ने 23 सितम्बर की रात्रि को ईरान-ईराक की सरकारों से आग्रह किया कि वे शीघ्र लड़ाई बन्द कर दें। बैठक का आयोजन राष्ट्रसंघ के महासचिव कुर्द वाल्दहीम के आग्रह पर हुआ। महासचिव ने भाषा का व्यक्त की थी कि दोनों देशों के बीच सीमा सम्बन्धी लड़ाई भागकर रूप धारण कर सकती है। सोवियत संघ ने ईरान और ईराक दोनों को सुझाव दिया कि वे शान्तिपूर्ण ढंग से अपने विवाद सुलझा लें ताकि पश्चिमी देशों को दखलान्दाजी करने का मौका न मिले। सरकारी पत्र प्रावदा ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीति के अन्तर्गत ईरान व ईराक के झगड़े से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने केलिफोर्निया में बोलते हुए सोवियत संघ को चेतावनी दी कि वह ईरान-ईराक के झगड़े में दखल न दे। उन्होंने धमकी भी दी कि खाड़ी के क्षेत्र में सोवियत सतरे का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त अमेरिकी शक्ति मौजूद है। कार्टर ने कहा कि अमेरिका पूरी तरह तटस्थता की नीति पर कायम है और अन्य देशों को भी यही नीति प्रपनानी चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि अमेरिका गव्यस्थता भी करने को तैयार है और उसे ईरान के इस आरोप की चिन्ता नहीं कि हमले के लिए उसी ने ईराक को भड़काया है।

बायजूद शान्ति और युद्ध-विराम की अपीलें के ईरान और ईराक के बीच लड़ाई जारी है, दोनों देशों ने एक-दूसरे को भारी क्षति पहुँचाई है। प्रस्तूबर, 1980 के प्रारम्भ में ईराक ने यह सवेत दिया कि चूँकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है अतः अपनी ओर से एकतरफा युद्ध-विराम कर देगा और यदि ईरानी आक्रमण जारी रहा तो आत्म-रक्षार्थ युद्ध करेगा। इसके जवाब में 4 प्रस्तूबर, 1980 को ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी ने कहा कि "ईरान बगदाद सरकार के अपराधों का बदला लेकर रहेगा और जब तक हमारी अन्तिम जीत नहीं हो जाती तब तक हम ईराक के साथ युद्ध-विराम नहीं कर सकते।" तथापि यह घोषणा की गई कि शीघ्र ही ईरान और ईराक के बीच युद्ध-विराम होकर शान्ति-वार्ता शुरू हो जाएगी। 1982 के प्रारम्भ तक यद्यपि दोनों राष्ट्र गुदरत हैं, तथापि छुट-गुट सैनिक भड़पों को छोड़कर युद्ध लगभग शान्त है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि तेजी से युद्ध पुनः नव भड़क उठे।

जब भी युद्ध होता है लोग प्रश्न करते हैं कि समुक्त राष्ट्र इसे क्यों नहीं रोकता? इस प्रश्न के उत्तर में अब तक के अनुभव के अनुसार समुक्त राष्ट्र से अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती। समुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देश ईरान-ईराक युद्ध को ही नहीं बल्कि हर युद्ध को विश्व शान्ति के लिए खतरा मानते हैं लेकिन इस युद्ध में दो देश सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बड़े देश स्थिति को और भी खतरनाक बना रहे हैं क्योंकि वे अपने आपको वहीं न वहीं इसमें उलभाये हुए हैं पर अभी तक बड़े देशों के सीधे युद्ध में शामिल होने का कोई मक़ेत नहीं मिला है।

उत्प्रेक्षणीय है कि ईरान इस मीके पर अपने की बहुत कुछ भकेला पा रहा है। उसके न अरब देशों में मित्र है और न पश्चिमी देशों में। सोवियत संघ से मदद की भी वह आशा नहीं कर सकता। आन्तरिक दृष्टि से वह कमजोर है, क्योंकि इस्लामी आन्ति के बाद से उसकी सेना तथा वायुसेना का संगठन गड़बड़ा गया है। उत्तर में कुर्द कबायलियों का विद्रोह पूरी तरह नहीं दबा है, क्योंकि वे अरब मूल के होने के कारण अपने को ईराक के अधिक निकट समझते हैं।

जहाँ नव भारत का सबान है, वह पश्चिमी एशिया में संघर्ष नहीं चाहता। उसमें बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप के वह त्रिस्तुल खिलाफ है। हिन्दमहासागर में बड़ी ताकतों की संधि उपस्थिति का वह इसीलिए विरोध कर रहा है। भारत की यह आशंका मान बलपना नहीं है कि बड़ी ताकतें पश्चिमी एशिया के स्थानीय सघर्षों में हस्तक्षेप करने के प्रलोभन से नहीं बच सकेगी, क्योंकि वे पुनः उस भू-भाग में अपने रर जमाना चाहती है। खाड़ी में संघर्ष का तो तत्काल असर होगा क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का अधिकांश तेल ईरान और ईराक से आयात करता है और अब पश्चिमी एशियायी देशों से हमारे घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध हैं। आशा करनी चाहिए कि दोनों देश अपने विवाद को युद्ध द्वारा हल करने से बचेंगे तथा शान्ति की खतरे में नहीं डालेंगे।

ईराक-ईरान सघर्ष का इतिहास

ईरान और ईराक का वर्तमान सघर्ष वास्तव में उमी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिणाम है कि अरब देशों में दबदबा किसका रहे? उचित होगा कि हम दोनों देशों के सघर्ष के इतिहास की रूपरेखा भी जान लें—

1968 में बाथ पार्टी के ईराक में सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गए थे, लेकिन मार्च 1975 में शाह ईरान और ईराक में तत्कालीन उप-राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने समझौता करने के बाद एक दूसरे को गले में लगाया। इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा सम्बन्धी समस्याओं पर सहमति हो गयी थी लेकिन कुछ मामले जहाँ के तहाँ छूट गए थे। इनमें से एक तो कुर्द समस्या थी और दूसरी शन-मल-अरब की समस्या प्रमुख थी। इस जल-मार्ग से जहाजों का आने-जाने का अधिकार दोनों ही देशों के लिए सुरक्षित माना गया था। इसके अलावा फारस की खाड़ी की अन्य समस्याओं पर भी उस समय में कोई सहमति नहीं हुई थी। 9 महीने बाद 120 मील लम्बे जलमार्ग में 50 मील के रास्ते का उपयोग करने पर फिर झगड़ा पैदा हो गया। ईराक इस बारे में 1937 की सन्धि रद्द करने पर जोर दे रहा था। इसके बाद तो सम्बन्ध पर ईरान और ईराक के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़े होने ही रहे हैं। 1971 में तीन खाड़ी द्वीपों पर बन्धा कर लिया था, जिसके बाद ईराक ने उनमें सैन्यिक सम्बन्ध तोड़ लिए थे। 1973 के अक्टूबर युद्ध में शाह ईरान ने ईराक को सीमा सम्बन्धी सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिए थे। शायद ईरान के शाह चाहते थे कि सीरिया की सहायता के लिए ईराक कम से कम अपने

दो डिवीजन भेजे। इन आश्वासनों के बाद ईराक ने ईरान से फिर राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिए।

जब-जब ईरान और ईरान के बीच सीमा-विवाद उठते रहे, अल्जीरिया उन्हें तय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जबकि मिस्र और कुर्दां, ईरान और ईराक के बीच भगडा तय कराने में कभी सफल नहीं हो सके। ईरान और ईराक के बीच एक-दूसरे से मिलती हुई सीमा काफी लम्बी है। 1913 के एक समझौते में दोनों देशों की आपसी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर निशान भी लगाए गए थे लेकिन धीरे-धीरे ये निशान मिटने गए और सीमा स्पष्ट नहीं रही, फिर कुर्दों की समस्या उठ खड़ी हुई। पिछली सदियों से इस समस्या ने और भी गम्भीर रूप धारण कर लिया। ईराक के उत्तर में पहाड़ों में कुर्दों से लड़ाई किसी न किसी रूप में चलती रहती है। बाथ पार्टी की सरकार ने 1977 में कुर्दों से एक समझौता किया, जिसके अन्तर्गत उन्हें चार वर्ष में स्वशासन देने का आश्वासन दिया गया। इस प्रश्न पर बातचीत काफी लम्बी चली और पिछले वर्ष मार्च में यह बातचीत टूट गयी। ईराक सरकार ने कुर्दों को उनकी समस्या के हिसाब से कुछ क्षेत्रों में स्वशासन देने की बात कही, लेकिन यह बात कुर्दों ने स्वीकार नहीं की। ईरान के शाह ने कुर्द विद्रोहियों को समर्थन भी दिया। शाह के शासनकाल में उनकी सरकार पर ईराक ने आरोप लगाया था कि लगभग एक लाख कुर्द ईरान चले गए हैं। ईरान उनकी सहायता भी कर रहा है और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण भी दे रहा है। अल्जीरिया ने दोनों देशों के बीच जो समझौता कराया था उसके अधीन ईरान को कुर्दों को समर्थन देना बन्द करना था लेकिन ईरान ने पूरी तरह ऐसा न करके विवाद की गुंजाइश बनी रहने दी थी। शाह के जमाने से ईरान ईराक की सत्ताधारी बाथ पार्टी को उपवादी कम्युनिस्ट संस्था मानता था। वह समझता था कि खाड़ी के क्षेत्र का केवल दो प्रतिशत ही ईराक के पाम है इसलिए उसे शत-अरब-अरब खाड़ी के जलमार्ग के प्रयोग का अधिकार ही है। उधर ईराक ओमान में ईरान के हस्तक्षेप को अपने लिए बहुत ही खतरनाक मानता है लेकिन कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात और लीबिया जैसे अन्य ईरान विरोधी अरब देश इस मामले में ईराक का साथ नहीं देते। दूसरी ओर लीबिया रुस के साथ ईराक के मंत्री सम्बन्धों को अनुचित मानता था। कुवैत का भी विचार है कि सोवियत संघ के साथ मित्रता के कारण ईराक अरब देशों के लिए खतरा है और 1961 में तो संयुक्त अरब अमीरात पर ईराक ने हमला करने की भी कोशिश की थी।

1975 में एक बार ईरान-ईराक का सीमा-विवाद अन्तिम रूप में तय हो गया था। उस समय समझा गया था कि अरब ईरान ईराक के बीच सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं रहा है। दोनों देशों के सीमा विवाद पर समझौता होने की घोषणा के बाद एक समिति गठित करने का भी एलान हुआ था, जो सीमा को अन्तिम रूप में तय कर देगा लेकिन इस समिति

के क्षमों में इंगन और ईराक के बीच वर्तमान भगड़ा होने तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। बताया जाता है कि 1913 के सन्धीन के आधार पर ही यह समझौदा भी हुआ था।

1979 में ईराक के नत्ताधारी इन बाय पार्टी की ओर ने ईरान पर ताडी क्षेत्र में अग्रिहार करने का आरोप लगाया गया था। इसने दोनों देशों के बीच फिर तनाव उत्पन्न हो गया। ईरान की ओर से इस तरह के आरोपों का सङ्कलन किया गया। साथ ही ईराक को चेतावनी भी दी थी कि यदि वह इस तरह आरोप लगाता रहा तो दोनों देशों के बीच शान्ति और मित्रता बनाए रखना मुश्किल होगा। उस समय ईरान की ओर से ओर देकर कहा गया कि अगर ईराक द्वारा हमला किया गया तो ईरान अपनी रक्षा करने में समर्थ है। साथ ही साथ ईरान ने ईराक पर यह आरोप भी लगाया था कि ईराक की सीमा से मिलने वाले खड्गस्त्रान में प्रख विद्रोहियों को ईराक सहायता दे रहा है। इस समय ईराकी विमानों द्वारा कुछ ईरानी गाँवों पर हमला भी करने के आरोप लगाए गए थे। जाहिर है कि ईराक ने इन नारे आरोपों का सङ्कलन किया था। नवम्बर 1979 में ही ईरान और ईराक के बीच तनाव शुरू हो गया था। उस समय भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले करने के आरोप लगाए थे। वर्तमान युद्ध ने पहले विद्वाने पर ईरान और ईराक की सीमाओं पर अनेक भडके होती रही। दली वर्ष अग्रेत में ईरान विदेश मंत्री श्री कुतुब जादे ने ईराक को अमेरिका का मिट्टू बनाया था और साथ ही यह घोषणा भी कर दी थी कि हमने ईराक की बाय पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। इंगन का कहना है कि तुम्बा और झाबू-भूमा के छोटे और बड़े द्वीप ईरान के अतिमित्र प्रग हैं, जिन पर ईराक ने 1971 में कब्जा कर लिया था। इनके पूर्व वे अग्र अमीरात के कब्जे में थे। ईराक इन्हें हथियाना चाहता है।

ईरान और ईराक की शत्रुता के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्यतः बबीना है। इनकी बड़ी सहा ईरान जा बसी है और वे अपने लिए एक प्रलग प्रान्त की माँग कर रहे हैं। वे तुर्की में भी हैं, जहाँ से वे कुर्दिस्तान माँग रहे हैं। इन्हीं को लेकर ईराक के तुर्की से तनावपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। वैसे दूसरे विश्वयुद्ध के बाद में ही ईरान और ईराक के बीच बटुना पैदा हुई है। यह बटुना कुछ समय के लिए ही कम होती है और फिर भडक उठती है। ईरान के अवातुल्ला खुर्मी की सरकार घाने ने धार्मिक भावनाई किया मुगलमानों में और भी तीव्र हो उठी है। ईराक में भी धार्मिक मुन्नी मुनलमान अल्पमत में है और शियाओं का उनके विरुद्ध होना स्वाभाविक ही है।



पूर्वी यूरोप मुख्यतः साम्यवादी प्रभाव में है। पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, अल्बानिया, बल्गेरिया, रूमानिया यूगोस्लाविया आदि पूर्वी यूरोपीय राज्यों में साम्यवादी सरकारें हैं और यूगोस्लाविया को छोड़कर शेष लगभग सभी साम्यवादी राज्य मास्को के पृष्ठपोषक माने जाते हैं। पूर्वी जर्मनी भी पूर्णतः रूसी प्रभाव में है। इनमें से अनेक साम्यवादी देशों में रूसी शक्ति से मुक्ति पाने के लिए समय-समय पर विद्रोह हुए किन्तु रूसी शक्ति और प्रभाव की सहायता से ये विद्रोह कुचल दिये गए। साम्यवादी जगत में पूर्वी यूरोप वस्तुतः एक समस्या-क्षेत्र बन गया है क्योंकि जहाँ पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राज्यों में उदारवाद पनप रहा है वहाँ सोवियत रूस इस उदारवाद को न पनपने देने के लिए कटिबद्ध है क्योंकि उसे आशंका है कि तब ये राज्य रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, पश्चिम की ओर झुक जाएंगे और इस प्रकार शक्ति सन्तुलन पूरी तरह पश्चिम के पक्ष में हो जाएगा। हिन्द महासागर पिछले कुछ वर्षों से अशान्त हो गया है क्योंकि इस क्षेत्र में महाशक्तियाँ अपने प्रभाव के विस्तार के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाए रखने के सभी प्रयास अभी तक असफल सिद्ध हुए हैं। अमेरिका और सोवियत सभ दोनों ही हिन्द महासागर में अपनी नौसैनिक तथा वैज्ञानिक गतिविधियाँ बढ़ा रहे हैं और चीन भी इस क्षेत्र में अधिकाधिक सक्रिय होता जा रहा है।

पूर्वी यूरोप

(Eastern Europe)

सोवियत संघ के सैनिक और राजनीतिक प्रयत्नों से पूर्वी यूरोप अधिकांशतः 'लाल' है। द्वितीय महायुद्ध में नाज़ी आक्रमण से बुरी तरह विध्वस्त होने के कारण रूस अपने पश्चिमी सीमान्त को इस तरह सुदृढ़ बनाना चाहता था कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके लिए आवश्यक था कि वह पूर्वी यूरोप में अधिकाधिक प्रदेश प्राप्त करे तथा सीमावर्ती राज्यों में अपने अनुकूल

साम्यवादी सरकारें स्थापित करे। रूस की लाल सेना ने इसमें बड़ा सहयोग दिया। अस्थायी रूप से लाल सेना ने युद्धकाल में मध्य और पूर्वी यूरोप के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और फिर शन-शन: इन सीमाओं को स्थायी बना दिया गया। अपनी सीमा पर रूस ने सात पृष्ठपोषक राज्य स्थापित किए—पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अल्बानिया, बल्गेरिया और रूमानिया—पूर्वी जर्मनी उसके संरक्षण में था और यूगोस्लाविया भी कुछ वर्षों तक सोवियत गुट में रहा। बाद में टोटो-स्टालिन मतभेद के कारण यूगोस्लाविया जून 1948 में सोवियत गुट से अलग हो गया। पूर्वी यूरोप को लाल बना देने से सोवियत संघ को न केवल पश्चिमी सीमा की सुरक्षा प्राप्ति हुई है अतः इन देशों की आर्थिक साधन-सम्पत्ति भी मिली है। जर्मनी के एकीकरण के पश्चिमी प्रस्ताव रूस को इसलिए स्वीकार नहीं हैं कि उनसे अन्य यूरोप में उसे लगभग दो सौ मील पीछे पूर्व की ओर हटना पड़ेगा।

पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुता का विस्तार कैसे और कहाँ तक हुआ इसका विवेचन हम 'सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश-नीति' नामक अध्याय में कर चुके हैं। यहाँ हम मुख्यतः यह देखेंगे कि समय-समय पर पूर्वी यूरोप के कुछ साम्यवादी देशों में हठी शिष्टों के विरुद्ध विद्रोह होते रहे हैं जिन्हें रूसी सहयोग न सम्बन्धित राज्य सरकारें चुलतती रही हैं। लेकिन यह प्रवृत्ति इस ओर संकेत करती है कि पूर्वी यूरोप 'स्वतन्त्रता की साँत' लेना चाहता है—सम्भवतः यूगोस्लाविया की भाँति साम्यवादी बना रहकर भी उन्मुक्त-प्रवस्था का उपभोग करना चाहता है। 1956 में हंगरी में विद्रोह हुआ जिससे सोवियत संघ ने सीधा हस्तक्षेप कर कुचन दिया। 1968 में सोवियत संघ तथा वारसा सन्धि के अन्य साम्यवादी देशों ने चेकोस्लावाकिया में सैनिक कार्यवाही कर हंगरी की घटनाओं को एक बार फिर ताजा कर दिया। चेकोस्लावाकिया में उदारवादी लहर को सोवियत संघ बर्दाश्त नहीं कर सका तथापि सोवियत नेताओं ने मूल कारण यही घोषित किया कि चेकोस्लावाकिया के साम्यवादी शासन को प्रतिक्रियावादी तत्त्वों से रक्षा करने के लिए सैनिक हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया था। सुरक्षा-परिपद् में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें रूसी कार्यवाही को एक स्वतन्त्र राष्ट्र पर आक्रमण की संज्ञा देकर उसकी निन्दा करते हुए यह भाँति की गई कि सोवियत संघ और वारसा राष्ट्रों की सेनाएँ चेकोस्लावाकिया से लौट जाएँ। किन्तु यह प्रस्ताव व्यर्थ सिद्ध हुआ और स्वयं चेकोस्लावाकिया की रूस समर्थक सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। यूगोस्लाविया कुछ ही वर्षों तक सोवियत रूस के प्रभाव में रहा और जून 1949 में ही मार्शल टोटो के नेतृत्व में स्टालिन की निरंकुशता ने मुक्त हो गया। पश्चिम देशों ने टोटो के इस विद्रोह का स्वागत किया तथापि यूगोस्लाविया पश्चिम के प्रभाव से भी उनी तरह मुक्त रहा जिस तरह वह सोवियत प्रभाव से रहा। सोवियत संघ से पृथक् रहते हुए और पश्चिमी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करते हुए भी मार्शल टोटो ने यह सदैव ध्यान रखा कि उनका राष्ट्र पूर्णतः एक स्वतन्त्र और सम्पूर्ण राष्ट्र रहे जो सोवियत या पश्चिमी प्रभाव से मुक्त प्रवस्था का उपभोग करे।

स्टालिन की मृत्यु के बाद यूगोस्लाविया के प्रति किसी क्षोभ समय के साथ कम होता गया और दोनों ही राष्ट्र अपने पारस्परिक सम्बन्धों पर पुनर्विचार करने की प्रेरित हुए। एक लम्बे अन्तराल के बाद यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो अगस्त 1977 में सोवियत संघ की राजकीय यात्रा पर गए और इस प्रकार दोनों देशों के बीच पुनः सद्भाव शुरू हुआ। सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव ने सितम्बर 1977 में यूगोस्लाविया की यात्रा की और वेलग्रेड में इस आश्वासन को दोहराया कि सोवियत संघ यूगोस्लाविया की स्वाधीनता का आदर करता रहेगा और यात्रा के बाद जारी की गई विज्ञप्ति में दोनों देशों के बीच 'रबैच्छिक सहयोग' की बात अंकित की गई। सोवियत संघ ने एक तरह से समाजवाद का अपना मार्ग अपने आप तय करने के यूगोस्लाविया के आग्रह को भी मान्यता दे दी। वास्तव में पूर्वी यूरोप में मार्शल टीटो ही एक ऐसे नेता थे जो विश्व में साम्यवादी आन्दोलन को विघटन से बचाने के लिए चीनी और सोवियत नेताओं से गम्भीर विचार-विमर्श के पक्ष में थे। उनमें क्षमता भी थी कि वे विश्व-साम्यवादी-आन्दोलन को नई दिशा और नई शक्ति दे सकें। 4 मई, 1980 को टीटो की मृत्यु हो गई तथापि यूगोस्लाविया का नया नेतृत्व टीटोवादी नीति पर चलते हुए सोवियत संघ और पश्चिम दोनों से मंत्री सम्बन्धों का निर्वाह करते हुए अपना पृथक् अस्तित्व बनाए रखने में प्रयत्नशील है।

पूर्वी यूरोप के एक अन्य साम्यवादी राज्य अल्बानिया का राजनीतिक जीवन विचित्र-सा रहा है। बाहरी दुनिया अब तक केवल इतना ही जानती है कि 8 नवम्बर, 1941 को अल्बानियाई कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, 29 नवम्बर, 1944 को फासीवाद के कब्जे से मुक्ति के बाद अल्बानिया में कम्युनिस्टों ने ही पहली सरकार बनाई और आज के पार्टी नेता एनवर होजा शुरू से ही अल्बानिया के भाग्यविधाता रहे हैं। 1944 से 1948 तक अल्बानिया यूगोस्लाविया का पार रहा, 1948 से 1961 तक अल्बानिया ने रूस की शागिर्दों की ओर 1961 से 1978 से चीन का सत्सर्ग किया। तत्पश्चात् कुछ समय तक अनिश्चय की डलमुल स्थिति के बाद अल्बानिया मार्च 1982 के अन्त तक बल्कान पहाड़ियों में एक प्रकार से वानप्रस्थ व्यतीत कर रहा है। अल्बानिया का यह राजनीतिज्ञ एकान्तवास कुछ विचित्र-सा है। 1981 में यह मुद्दे में आया था कि ईरान के शाय्यातुल्ला खुमेनी की खूनी क्रान्ति से अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ता है और ईरान से सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रहा है। धेनुकी होते हुए भी यह विशेष आश्चर्य की बात नई प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अल्बानिया भी मूलतः एक मुस्लिम देश है और पार्टी नेता एनवर होजा ने भी अपनी जनता का जैसे ही पानी की तरह खून बहाया है जैसे खुर्गनी ने, और दोनों जेप दुनिया द्वारा एक ही सामान निन्दित एवं उपेक्षित नेता हैं।¹ 1981 के अन्तिम चरण में तिराना में अल्बानियाई कम्युनिस्ट

पार्टी का 8वाँ पार्टी अधिवेशन हुआ था। एनवर होजा ने इस अधिवेशन के दौरान पार्टी के पोलिनियूरो में कई परिवर्तन किए और कई नए लोगों को कम्युनिस्ट सत्ता के इस सर्वोच्च निकाय में बैठाया। इस अधिवेशन में एक बार फिर उन्होंने रुम, चीन और यूगोस्लाविया को एक ही पंक्ति में बैठा कर 'मशोधनवादी' और 'पयभ्रष्ट' घोषित किया, यूरोकम्युनिस्टों को 'माओवाज्वाद के भांडे के टट्टू' करार दिया और अपने मुँह मिया मिट्टू बनते हुए कहा कि सच्चा मार्क्सवाद-लेनिनवाद केवल अल्बानिया में ही रह गया है।

पोलैण्ड (पोल्स्का) को पूरी तरह अपने प्रभाव में बनाए रखने के लिए रुम निरन्तर चौकन्ना रहता है क्योंकि यह सीमावर्ती राज्य रुम की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैण्ड के साथ भी रुम की मैनिफेस्ट सन्धि है और पोलैण्ड-वारसा पैंक्ट का शक्तिशाली मददगार है। पोलैण्ड के मजदूर (पोल्स्की मजदूर) काफी अरसे से फौजी शासन का विरोध कर रहे हैं और रुम को यह भय मना रहा है कि मजदूरों का विद्रोह वही पोलैण्ड में रुम समर्थक सरकार को उखाड़ न दे। दिसम्बर-जनवरी, 1982 में दिनमान की टिप्पणी थी—“रुम की सम्वाद एजेन्सी ‘ताम’ से मिलने वाली खबरों तथा पुष्ट सूत्रों ने प्राण जानकारी के अनुसार हडतालें जारी हैं, जहाँ-तहाँ मजदूर मारे और पकड़े गए हैं तथा दमनचक्र में मोदियत मष की शिकायत बढ़ती जा रही है।” पोलैण्ड की मोदियतनोश्च नामक शक्तिशाली मजदूर यूनियन के श्रीरस्थ नेता सम्भवतः नजरबन्द है। यद्यपि पोलैण्ड के देशव्यापी आन्तरिक संकट का भरपूर गवनीनिक ताम अमेरिका और उसके भावी राष्ट्र उठाने को उत्सुक है तथापि पूर्वी यूरोप रुम का प्रभावक्षेत्र है अतः कोई भी विदेशी राष्ट्र पोलैण्ड को रुम के चंगुल में छुटाने की कोशिश नहीं करेगा। यह सम्भव है कि अमेरिका मोदियत संघ पर आर्थिक दबाव डाले—अनाज के निर्यात और व्यापारिक लेन-देन पर अनुज्ञ नगाकर तनाव पैदा करे। वैसे 24 दिसम्बर, 1981 को जब राष्ट्रपति रीगन ने पोल्स्का-अमेरिका व्यापार पर प्रतिबन्धों का एलान किया तो मोदियत संघ ने बाकायदा आरोप लगाया कि यह पोल्स्का में हस्तक्षेप है। जनवरी 1982 के दिनमान की टिप्पणी थी . पोल्स्का में कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी मजदूर आन्दोलन ने जितनी तत्काली मोदियत मष को हो रही थी उससे अधिक मुशी अमेरिका को थी—स्वाधीनता-प्रेमी होने के नाते उनकी नहीं जितनी इस नाते कि अन्तर्विरोध एक विस्फोटक स्थिति में पहुँच कर रुम को चुनौती दे रहे हैं। पोल्स्का लोगों के आन्दोलन से महानुभूति दिखाकर अमेरिका को चीनमुद्र तंत्र करने में मदद मिल रही थी—और अब फौजी हस्तक्षेप के बाद और भी मिल रही है। इस घटना से यूरोप और अमेरिका के अन्तर्विरोध भी सामने आ सकते हैं। शक्ति-सन्तुलन की गवनीनिक में विश्वास करने वाली महती शक्तियाँ एक-दूसरे के हितों और प्रभावक्षेत्र को बखूबी पहचानती हैं और उसमें दखल देने का दुस्साहस नहीं दिखातीं। अमेरिका सरकार ने साक्षात् सहायता पर प्रतिबन्ध लगाकर एक औपचारिकता निभायी है।

लेकिन यूरोपीय समुदाय के पड़ोसी देशों का पोल्स्की लोगों के प्रति दुमरा रव है। उन्होंने पोल्स्की जनों के समर्थन में लाख पदार्थ भेजते रहने की इच्छा व्यक्त की है।

जब अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों ने साम्यवाद के विरोध में नाटो सैनिक संगठन की स्थापना की तो रूस से पीछे रहने की आशा नहीं की जा सकती थी। दिसम्बर, 1954 में आठ यूरोपीय देशों अर्थात् अन्वलिषा, बेल्जियम, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैण्ड, रूमानिया, सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन के पर्यवेक्षकों का सम्मेलन पेरिस शान्ति सन्धियों के प्रति अपने रवों पर विचार करने के लिए हुआ। सम्मेलन ने सन्धियों के पुष्टिकरण का विरोध करते हुए घोषणा के बावजूद जब पेरिस सन्धियों की पुष्टि की गई तो आठो देशों ने वारसा में 11 मई से 14 मई, 1954 तक चार दिन की अपनी बैठक में लम्बे विचार-विमर्श के बाद मैत्री, सहयोग तथा पारस्परिक सहायता की सन्धि की जो वारसा पैक्ट 1955 के नाम से विख्यात है।

यह सन्धि जिसे वारसा सन्धि या पूर्वी यूरोपियन सन्धि संगठन के नाम से सम्बोधित किया जाता है, 20 वर्ष के लिए की गई। इसका उद्देश्य पारस्परिक शक्ति के प्रयोग से बचे रहना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण उपायों से निपटारा करना है, परन्तु साथ ही इसमें सदस्य राष्ट्रों को बाह्य आक्रमण के समय सामूहिक सुरक्षा की गारन्टी दी गई है। सन्धि की प्रस्तावना एवं कुछ प्रमुख धाराएँ इसके प्रधान स्वरूप व इसकी शक्ति को व्यक्त करती हैं। सन्धि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा पद्धति स्थापित करने पर बल देते हुए कहा गया है कि पश्चिमी यूरोप के मध्य एवं पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण से यह आवश्यक हो गया है कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करें तथा यूरोप में शान्ति कायम रखें। इस दृष्टि में इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में घनिष्ठ सहयोग का वर्णन है। सन्धि की धारा 1 में कहा गया है कि इसके सदस्य शक्ति का प्रयोग करने से बचे रहने का प्रयत्न करेंगे और यह घोषणा भी करते हैं कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शान्तिपूर्ण उपायों से करेंगे, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि हंगरी के मामले में 1956 के इस मिद्दान्त की उपेक्षा की गई। धारा 3 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होना है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। धारा 4 के अनुसार "यदि यूरोप में सन्धि करने वाले एक अथवा अनेक राज्यों के विरुद्ध कोई सैनिक आक्रमण एक या अनेक राज्यों के द्वारा हो तो सन्धि करने वाले प्रत्येक सदस्य राज्य से आक्रमणकारी राज्य अथवा राज्यों के लिए शीघ्र ही स्वयं ही सहायता करेगा अथवा सदस्य राज्यों के समझौते से उन सभी प्रकार के साधनों को जो आवश्यक हो और आवश्यकता के समय वह सैनिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार रहेगा।" धारा 5 के अनुसार सन्धिकर्ता शक्तियों ने एक सामूहिक शक्ति को निर्माण करने का, जिसका प्रयोग सामूहिक समझौते के अनुसार किया जाएगा, निश्चय किया। इस प्रकार धारा 5 में एक संयुक्त सैनिक कमान (United Military Command)

बनाई गई है जिसके अधीन सब देशों की सेनाएँ होगी और जिसका एक सर्वोच्च मेनापति होगा जो महामन्त्री तथा सोवियत जनरल स्टॉक के साथ परामर्श करके सेनाओं का संगठन और विभिन्न प्रदेशों में इसका वितरण करेगा। यूरोप में इसकी उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी यूरोप की तीन कमानों और सुदूरपूर्व की एक कमान रखी गई है। धारा से 6-8 में शक्ति की 'राजनीतिक परामर्शदात्री समिति' (Political Consultative Committee) द्वारा सब सामान्य प्रश्नों पर विचार करने की सहायक संस्थाएँ स्थापित करने की और वर्ष में दो बार बैठक करने की व्यवस्था है। इस समिति के महामन्त्री का कार्यालय मास्को में है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अध्ययन करने तथा विदेश नीतियों के बारे में आवश्यक निष्कारिणों करने के लिए 1956 में एक स्थायी आयोग भी कायम किया गया था। वारसा सन्धि ने अपनी उदारता व्यक्त करने के लिए धारा 9 में यह व्यवस्था दी है कि यह सन्धि सामाजिक अथवा राज्य संगठन के प्रकार की ओर ध्यान न देकर राज्यों के लिए भी खुली हुई है जो इस सन्धि की शर्तों के अनुसार अन्य राष्ट्रों की शान्ति और सुरक्षा के लिए तैयार है। इस प्रकार वारसा सन्धि नाटो का पूरा एवं सशक्त जवाब है। इस सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि सन्धि करने वाले सभी राज्य केवल रूस के अनुयायी माने हैं। यूगोस्लाविया ने साम्यवादी होते हुए भी इस सन्धि में भाग नहीं लिया और इससे पृथक् रह कर ही अपनी आर्थिक स्थिति को उच्चतर बनाया।

अन्त में यह बात और उल्लेखनीय है कि वारसा सन्धि के अनिर्दिष्ट भी समस्त साम्यवादी देशों—यूगोस्लाविया, पोलैण्ड, रूमानिया, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, बल्गेरिया और फिनलैण्ड ने पारम्परिक सहायता की 20 और सन्धियाँ कर रखी हैं।

हिन्द महासागर (Indian Ocean)

भूगोल और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

हिन्द महासागर तथा उसके तटवर्ती क्षेत्र भूराजनीतिक दृष्टि से सदैव से महत्वपूर्ण रहे हैं, परन्तु गत कुछ समय से इसका महत्व विशेष उल्लेखनीय हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता का यह एक विवादग्रस्त क्षेत्र बन गया है तथा शान्ति भंग होने का डर अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। हिन्द-महासागर के लिए राजनीतिक होड़ और भी तेज हो गई है क्योंकि अमेरिका, रूस तथा चीन इस पर प्रभुत्व स्थापित करने की पूर्ण चेष्टा में हैं। दूसरी ओर हिन्द-महासागरीय देशों की यह इच्छा है कि एक शान्तिमय क्षेत्र बना रहे और इस पर वास्तविक अधिकार अफ्रीका तथा एशिया के तटवर्ती देशों का होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में हिन्द-महासागर अपना विशेष स्थान रखता है। यह कहना अनिश्चयान्वित नहीं होगी कि अब यह महासागर शीतयुद्ध का प्रमुख क्षेत्र हो गया है।

हिन्द-महासागर पृथ्वी पर एक प्रमुख महासागर है जिसका क्षेत्रफल लगभग 73 करोड़ वर्ग किलोमीटर है जो एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में घिरा हुआ है तथा दक्षिण में इसका सीमा क्षेत्र अंटार्कटिक महासागर बनाता है।

दक्षिणी सीमा निर्धारित करना समस्यापूर्ण है, परन्तु यह कहा जा सकता है कि हिन्द-महासागर की दक्षिणी सीमा लगभग 450 दक्षिणी अक्षांश के नीचे तक है या पश्चिमी वायु धारा (वंस्ट विंड डिप्ट) इसको अटार्कटिक महासागर से अलग करती है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई लगभग 10,400 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 9600 किलोमीटर है। हिन्द-महासागर पृथ्वी के सम्पूर्ण जल-मण्डल का 19 प्रतिशत भाग बनाता है।

हिन्द-महासागरीय तटवर्तीय देशों की संख्या लगभग 40 है। ये देश अफ्रीका, एशिया तथा आस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में स्थित हैं। तटवर्ती क्षेत्र का विस्तार लगभग 22 करोड़ वर्ग किलोमीटर है जो कि ससार के जलमण्डल का 15 प्रतिशत भाग बनाता है। हिन्द-महासागरीय क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या (1971) लगभग 106 करोड़ है जो कि ससार की जनसंख्या का 30 प्रतिशत है। इसमें अकेले एशियाई क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 93 करोड़ है। भारत, बंगलादेश, इण्डोनेशिया जनसंख्या की दृष्टि से प्रमुख हैं। अफ्रीकी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है और उसमें दक्षिणी अफ्रीका, दक्खिनीय और कजानिया जनसंख्या की दृष्टि से प्रमुख हैं।

हिन्द-महासागर को भौगोलिक दृष्टि से दो प्रमुख क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है—पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र जिनका सीमा-विभाजन मध्य हिन्द-महासागरीय जलमग्न श्रेणी के आधार पर किया जा सकता है। यह जलमग्न श्रेणी उत्तर से लक्षदीव, मालदीव से आरम्भ होकर सुदूर दक्षिण में 77° और 80° पूर्वी देशान्तरों के मध्य में जाती हुई समाप्त होती है। पश्चिमी क्षेत्र में श्रीलंका, बेरिनि तथा गिन्थु जलमग्न शृङ्खला प्राकृतिक भण्डार के प्रमुख क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र में गंगा जलमग्न शृङ्खला क्षेत्र इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। अफ्रीका के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों में मेडागास्कर जलमग्न क्षेत्र प्रमुख है और पूर्व में ग्रंडमान निकोबार जलमग्न क्षेत्र विशेष हैं।

जलमग्न श्रेणियों की स्थिति और फैलाव के कारण हिन्द-महासागर में अनेक द्वीप हैं जो कि राजनीतिक एवं नौ-सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये द्वीप इतिहास में विशेष रूप से 17वीं शताब्दी से प्रमुख रहे हैं। इन्हीं के आधार पर यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने अफ्रीका तथा एशिया के देशों पर आतंक तथा नियंत्रण रखी थी। हिन्द-महासागर के प्रमुख द्वीपों में ये विशेष उल्लेखनीय हैं—सकोनरा, मालदीव, लक्षदीव, मारिजस, मेडागास्कर, त्रिनिदी हिन्द-महासागरीय क्षेत्र के द्वीप अलदात्रा, देनोचस, फार्कुहार, डियागो गार्सिया तथा रियूनियन आदि द्वीप पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में ग्रंडमान, निकोबार, कोकोस तथा किंगमस द्वीप। इन्हीं द्वीपों के आधार पर तथा त्रिनिदी साम्राज्य के विस्तार के आधार पर हिन्द-महासागर को ब्रिटेन की भीड़ कहा जाता था, परन्तु 1966 में ब्रिटेन के इस निर्णय के बाद से कि वह स्वेज के पूर्व से अपना सैनिक उत्तरदायित्व समाप्त कर देगा। ये द्वीप अमेरिका के सैनिक अड्डे बनते जा रहे हैं। श्रीलंका हिन्द-महासागर का एक विशेष महत्व का द्वीप रहा है और उसमें निकोमाली का प्राकृतिक बन्दरगाह अद्वितीय है तथा

हिन्द-महासागर की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के लिए इसको संसार की महाशक्तियाँ प्रमुखता देती हैं और कोशिश में हैं कि उसके ऊपर उनका अधिकार रहे।¹ जलमार्ग एवं तटवर्ती देश

हिन्द-महासागर पूर्व में प्रशान्त महासागर से मलक्का जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है और पश्चिम में अरब-महासागर से भूमध्यसागर, स्वेज नहर तथा दक्षिणी अफ्रीका के केप मार्ग द्वारा जुड़ा है। 1967 की अरब-इजरायल लड़ाई के बाद से स्वेज नहर बन्द है, अतः केप जलमार्ग का व्यापारिक तथा सैनिक महत्त्व अधिक हो गया है। हिन्द-महासागर की मध्य स्थिति होने के कारण एवं तीन महाद्वीपों—एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण ये हमेशा जलमार्गों के लिए महत्त्वपूर्ण जलक्षेत्र हैं। प्रधान जलमार्गों में प्रमुख हैं—केप-कोलम्बो-सिंगापुर मार्ग, कोलम्बो—पर्य मार्ग, केप अफ्रीका का तटीय जलमार्ग, केप-बम्बई तथा कराची मार्ग और स्वेज-अदन-कोलम्बो-सिंगापुर मार्ग सुदूर पूर्व और पश्चिमी-उत्तरी अमेरिका को हिन्द-महासागर से जोड़ता है। ये हिन्द-महासागरीय जलमार्ग एशिया के प्रमुख प्राकृतिक साधन भण्डारों के क्षेत्रों को यूरोप तथा अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ते हैं और व्यापारिक दृष्टि से प्राथमिक समझे जा सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन के वितरण के लिए ये जलमार्ग प्रमुख आयातवर्ती देशों से यूरोप तथा अमेरिका के क्षेत्रों को सम्बन्धित करते हैं, अतः यह अनिवार्य है कि ये जलमार्ग सुरक्षित रहे और इनका व्यापारिक महत्त्व कम न हो पाए। इन अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा अनेक महत्त्वपूर्ण तटीय जलमार्ग हैं जो हिन्द-महासागरीय देशों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित रखते हैं। यदि हिन्द-महासागरीय देशों का आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टि से एक समूह बनाया जाए तो इन तटीय जलमार्गों का महत्त्व भविष्य में कई गुना बढ़ जाएगा। वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर परिपूर्ण सन्त मिलते हैं कि निकट भविष्य में हिन्द-महासागरीय देशों में आर्थिक तथा व्यापारिक संगठन बनेंगे, क्योंकि इसी में सामूहिक उत्पादन की आशा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये तटीय जलमार्ग विशेष उल्लेखनीय हैं।

हिन्द-महासागर के महत्त्व को स्पष्ट करने के लिए यह अनिवार्य है कि उससे तटवर्ती देशों तथा क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। हिन्द-महासागरीय तटीय क्षेत्रों का अध्ययन अनिवार्य है जिसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि हिन्द-महासागर का भविष्य क्या होगा? तटीय प्रदेश तथा देश भू-राजनीतिक दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखते हैं। लगभग तमाम तटीय देश दूसरे महायुद्ध के आस-पास यूरोप के देशों के अधिकार में थे और वहाँ के उद्योग धन्यों के लिए प्राकृतिक साधनों के भण्डार और स्तम्भ थे। उन देशों के स्वाधीन हो जाने के बाद भी यूरोप और अमेरिका के देश इनको अपने उद्योग-धन्यों का स्तम्भ बनाए रखना चाहते हैं और विरसानीन आर्थिक दासता को तत्काल नहीं होने देना चाहते हैं। हिन्द-महासागरीय देशों को इन

1 भारत, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, नयी दिल्ली के श्री गणेशदास शर्मा के विशेष लेख में।

प्रमुख प्रदेशों में बांटा जा सकता है—अफ्रीका प्रदेश, मध्यपूर्व, हिन्दुस्तान का प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वेशिया तथा आस्ट्रेलिया प्रदेश। आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका को छोड़ कर अन्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अर्द्धविकसित हैं और प्राकृतिक आर्थिक मापनों के भण्डार हैं। औद्योगिक विकासविहीन होने के कारण इन देशों में रहन-सहन का आर्थिक स्तर शोचनीय है और जनसंख्या का घनत्व और वृद्धि की गति अधिक है। वार्षिक जनसंख्या की वृद्धि गति गम्भीर है। जनसंख्या के घनत्व तथा वार्षिक वृद्धि गति के आधार पर हिन्द-महासागरीय देशों को चार प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है—(अ) अधिक घनत्व या अधिक वार्षिक वृद्धि के क्षेत्र—भारत, बंगलादेश, इण्डोनेशिया आदि, (ब) कम घनत्व तथा साधारण वार्षिक वृद्धि के क्षेत्र—दक्षिण पश्चिम आस्ट्रेलिया, (स) कम घनत्व तथा अधिक वार्षिक वृद्धि के क्षेत्र—दक्षिण अफ्रीका, केन्या, जाम्बिया, तंज़ानिया आदि तथा (द) साधारण घनत्व तथा अधिक वार्षिक वृद्धि क्षेत्र—सोमालिया, अरब, ईरान, उर्गांडा आदि। ये सभी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से असम्पूर्ण क्षेत्र हैं तथा इनका उत्थान तभी हो सकता है जबकि आवासी की वार्षिक वृद्धि गति रोकी जाए और आर्थिक उत्पादन बढ़ाया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय घुसपैठ का क्षेत्र, सैनिक महत्त्व एवं क्षेत्रीय सहयोग

हिन्द महासागर काफी समय तक ब्रितानी मील बना रहा परन्तु द्वितीय महायुद्ध के बाद इसमें राजनीतिक परिवर्तन हुए और स्पर्धा तथा वैमनस्य के कारण अन्तर्राष्ट्रीय घुसपैठ का क्षेत्र बन गया। आर्थिक क्षियलता और निम्न स्तर के अलावा यहाँ पर राजनीतिक विच्छिन्नता भी है। भारत, दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के अलावा इस क्षेत्र के देशों में राजनीतिक स्थिरता की कमी है। अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम और पूर्वेशिया में सरकारें रोज बदली जाती हैं या खतरे में रहती हैं। पश्चिमी देशों ने पारस्परिक ऋण और वाद-विवाद के ऐसे कई मसले छोड़ दिए हैं कि हिन्द-महासागरीय क्षेत्र में शान्ति तथा पारस्परिक विकास दुर्लभ दिखाई देता है। महाशक्तियों की कूटनीति इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन उथल-पुथल की सम्भावना बनाए रखती है।

अतः राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से हिन्द महासागरीय क्षेत्र एक रुचिपूर्ण क्षेत्र है। केन्द्रस्थ सांघोतिक स्थिति होने के कारण यह सैनिक दृष्टि में भी महत्त्वपूर्ण है। उत्तर में रूस और पूर्व में चीन की स्थिति और ब्रिटेन की अनुपस्थिति में हिन्द महासागर अमेरिका के लिए विशेष सैनिक महत्त्व रखता है। इसके अलावा यदि हिन्द महासागर को भू-राजनीतिक मानचित्र में देखें तो यह कहना प्रतिशयोक्ति न होगी कि यह सैनिक दृष्टि से वह क्षेत्र है जहाँ रूस और अमेरिका को वस्तुतः तटस्थ होना चाहिए, परन्तु वे पारस्परिक वैमनस्य के आधार पर अपनी शक्ति इस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। यह शक्तिवर्द्धन दो प्रकार से हो रहा है। पहला, हिन्द महासागरीय क्षेत्र के देशों को अमेरिका कई प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक संगठनों में बाँधे हुए हैं। जवाहरण के लिए सेंटो तथा सीएटी संगठन विशेष उल्लेखनीय हैं जिनके आधार पर अमेरिका मध्यपूर्व या दक्षिण पश्चिम एशिया

के एक विशेष क्षेत्र को अपने कब्जे में किए हुए है ताकि इस क्षेत्र में रूस का आधिपत्य न होने पाये। सीएटो संगठन दक्षिणपूर्व क्षेत्र के देशों को अमेरिका के साथ बांधे हुए हैं। इस प्रकार के सैनिक संगठनों द्वारा अमेरिका द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से साम्यवाद के विस्तार पर अकुश लगाए रखने का प्रयास करता रहा है। दूसरा, इन विविध प्रकार के संगठनों के माध्यम से अमेरिका हिन्द महासागर में खुलने वाले प्रमुख जल द्वारों को अपने नियन्त्रण में रखना चाहता है। जैसे दक्षिण पूर्वशिया में मलक्का जलमार्ग जो कि हिन्द महासागर को प्रशान्त महासागर तथा उसके तटीय देशों से मिलाता है। आर्थिक, व्यापारिक तथा सैनिक दृष्टि से मलक्का मार्ग अद्वितीय है। दक्षिण पश्चिम एशिया में अमेरिका तथा ब्रिटेन स्वेज तथा अदन जल मार्गों पर नियन्त्रण रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के दल पर अमेरिका तथा ब्रिटेन केप जलमार्ग पर प्रभुत्व कायम किए हुए हैं।

दक्षिण पश्चिम एशिया में अमेरिका के विरुद्ध रूस का प्रयास काफी शक्तिशाली है। रूस इसके लिए प्रयत्नशील है कि इस विशेष क्षेत्र में उसका बोलबाला रहे ताकि उसका प्रभुत्व हिन्द महासागर पर दिन प्रतिदिन अधिक मजबूत बने। दक्षिण पूर्वशिया के क्षेत्रों में चीन का आतंक अधिक है और आशंका है कि चीन दक्षिण पूर्वशिया पर सदैव नियन्त्रण बनाए रखने की चेष्टा में है।

अफ्रीका के क्षेत्र में कई ऐसे पहलू हैं जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तथा चीन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए ये देश प्राकृतिक आर्थिक साधनों के प्रमुख भण्डार हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और पक्के भाल की खपत के लिए आशाजनक क्षेत्र हैं अतः ये राष्ट्र पारस्परिक जलन, वैमनस्य और आर्थिक लाभ की होड़ में हैं।

महाशक्तियाँ अपने प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए हिन्द महासागर तथा उसके तटीय क्षेत्रों में सैनिक अड्डे भी बनाए हुए हैं और इस प्रयत्न में है कि किस प्रकार इस क्षेत्र में और शक्तिशाली बनें। साइमन्स टाउन सैनिक अड्डे से डिपानो गासिया तथा क्रिस्मस द्वीप अड्डे तक अमेरिका ब्रिटेन की सहायता से 'रायल रोड' बनाये हुए हैं जो सैनिक दृष्टि से अद्वितीय हैं। इसके अलावा अमेरिका सेंटो तथा सीएटो देशों में, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में हवाई तथा समुद्री सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि अमेरिका हिन्द महासागरीय क्षेत्र में अपना सैनिक आधिपत्य रूस आदि की तुलना में मजबूत रखना चाहता है। दूसरी ओर रूस तथा चीन इस प्रयत्न में हैं कि किस प्रकार अपनी सैनिक क्षमता हिन्द महासागर में बढ़ाएँ।

भारत-रूस और (व० 71) और बंगलादेश का अम्युदय हिन्द महासागर के लिए एक नए युगल देशरम्भ होने के द्योतक हैं जिसके द्वारा रूस की पहुँच सीधी हिन्द महासागर तक हो गई है। हिन्दुस्तान प्रायद्वीप में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं वे रूस को अमेरिका के विपरीत लाभप्रद हैं और रूस की क्षमता हिन्द महासागर भविष्य में बढ़ सकती है।

आर्थिक, व्यापारिक तथा पारस्परिक सहयोग की दृष्टि से हिन्द महासागरीय क्षेत्र इसके तटीय देशों के लिए महत्वपूर्ण है। महाशक्तियों के अलावा हिन्द-महासागरीय देशों की रवि कई प्रकार से बढ़ती जा रही है। निःसन्देह यह क्षेत्र प्राकृतिक आर्थिक माधनो के कारण भविष्य का आशाजनक क्षेत्र है। पारस्परिक आर्थिक उत्थान के लिए इस क्षेत्र के देश इन कोशिश में हैं कि किस प्रकार महाशक्तियों के घगुन से बचे रह कर आपसी सहयोग के द्वारा उन्नति की जाए। भारत, दक्षिण अफ्रीका, इण्डोनेशिया, बंगलादेश आदि ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी रवि इसमें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनके अलावा जापान और आस्ट्रेलिया भी प्रयत्नरत हैं।

स्पष्ट है कि हिन्द महासागर अन्तर्राष्ट्रीय घुसपैठ का भड़ा बन गया है। पारस्परिक वंमनस्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब यह किसी भी मापदण्ड से शान्तिमय क्षेत्र नहीं रहा है। भू-राजनीतिक दृष्टि से हिन्द महासागर पर क्षेत्रीय देशों का सहयोगपूर्ण आधिपत्य रहना चाहिए। आर्थिक और व्यापारिक संगठन बनाना आवश्यक है अन्यथा विदेशी पूंजी और महाशक्तियों की पूठनीति हिन्द-महासागरीय क्षेत्रों की उन्नति में बाधक बनी रहेगी।

हिन्द महासागर और बड़ी ताकतों तथा भारत की नीति

हिन्द महासागर के आस-पास के देशों ने बड़ी ताकतों से अनेक बार अनुरोध किया है कि वे इस क्षेत्र को अपने पक्षधर्मों का केन्द्र न बनाएं और इसे शान्ति-क्षेत्र बना रहने दें। लेकिन ये बड़ी ताकतें अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की होड़ में बार-बार इस अनुरोध को ठुकरा कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करती रही हैं। इजरायल और मिस्र की शान्ति-सन्धि तथा अरब देशों द्वारा इस सन्धि का विरोध, ईरान में सत्ता परिवर्तन, अफगानिस्तान की शान्ति तथा उसे विफल बनाने की अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की साजिशों ने इस क्षेत्र को ताकत आजमाइश का क्षेत्र बना लिया है और इस प्रकार इस क्षेत्र की शान्ति को खतरे में डाल दिया है। ऐसा मान्य पड़ता है कि अमेरिका ने हिन्द महासागर के लिए एक नया समुद्री-वेड़ा तथा सैनिक भड़ा तैयार करने का निश्चय किया है। सोवियन संघ के सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने हिन्द महासागर के क्षेत्र में जो गतिविधियाँ आरम्भ की हैं, उनके कारण उसे भी अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना आवश्यक हो गया है। स्पष्ट है कि सोवियन संघ हिन्द महासागर की मार्फन सुदूरपूर्व के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकता है।

हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों के प्रवेश और भारत की नीति पर भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय की 1980-81 वार्षिक रिपोर्ट इस प्रकार है—

“हिन्द महासागर के क्षेत्र में आज जितने बड़े पैमाने पर बड़ी शक्तियों द्वारा सैनिक जमाव किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ है। इस बड़ी हुई सैनिक उपस्थिति को उचित सिद्ध करने के लिए इस क्षेत्र की हाल की घटनाओं का बहाना लिया गया है। इस जमाव में डियागो-गार्सिया के अड्डे का विस्तार और इस आशय का कथित निर्णय भी शामिल है कि इसे एक प्रमुख वायु एवं नौसैनिक

अड्डे के रूप में, और सम्भवतः नाभिकीय सुविधा के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इस निर्णय के साथ-साथ ही प्रमुख गैर-तटवर्ती शक्तियों ने इसमें तेजाव अपने नौ-सैनिक जहाजों और सैनिक विमानों की संख्या में वृद्धि कर दी। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी मुख्य रूप से हिन्द महासागर में प्रयोग के लिए एक लाख दस हजार कामिको वाली एक द्रुतगति सेना तैयार करने की योजनाओं का एलान किया। तटवर्ती पत्तनों पर ईंधन भरने, पुनःभरण तथा विश्राम और मनोरंजन की सुविधाएँ हासिल करने की चेष्टाओं और अड्डे की सुविधाएँ अर्जित करने के प्रयासों से भारत और दूसरे गुट-निरपेक्ष राज्यों में गम्भीर चिन्ता उत्पन्न हो गई है।”

दूसरी बड़ी शक्तियों यानी सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की नौ-सैनिक उपस्थिति में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके प्रतिरिक्त इस आशय की भी खबरें मिली हैं कि ऐसी सुविधाएँ हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं जिनके अन्तर्गत नौ-सैनिक कामिको को ज्यादा लम्बे अरसे तक और ज्यादा सत्या में तैनात रखना मुमकिन हो सकेगा।

भारत ने हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति का बराबर विरोध किया है क्योंकि उसके पड़ोस में नए सघर्ष पैदा होते हैं और उनकी शान्ति और स्थायित्व के लिए खतरा पैदा हो जाता है। हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने से सम्बद्ध 1971 की घोषणा को शीघ्र क्रियान्वित कराने की दिशा में भारत दूसरे गुट-निरपेक्ष और तटवर्ती पश्चिम राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस उद्देश्य से भारत हिन्द महासागर सम्बन्धी तदर्थ समिति में यह सहमति कराने की दिशा में भी कोशिश कर रहा है कि हिन्द महासागर के सम्बन्ध में श्रीनका सम्मेलन अपने पूर्व-निश्चित कार्यक्रम के अनुसार बुलाया जाए।

हिन्द महासागर में आणविक युद्ध का खतरा

अप्रैल 1981 में प्रख्यात लेखक श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिससे हमें हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों की गतिविधियों, भारतीय चिन्ता और इस क्षेत्र में आणविक युद्ध के खतरे आदि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी मिलती है। श्री चतुर्वेदी का लेख इस प्रकार है—

“प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कई बार भारत के चारों ओर बढ़ते हुए सैनिक सतरो की बातचीत की है। सम्भवन राजनीतिक शिष्टाचार के कारण श्रीमती इन्दिरा गाँधी अपनी बात को खुलकर नहीं कह सकी। यह समझने के लिए कि भारत के चारों ओर खतरा कितना बढ़ रहा है हमें अमेरिकी सूत्रों पर ही ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। हाल ही में यानी 24 मार्च, 1981 को अमेरिका के प्रतिनिधि सदन के समक्ष निकट पूर्व और दक्षिण एशिया के लिए अमेरिका की विदेश उपमन्त्री जैन एनून ने यह बताया है कि वित्तीय वर्ष 1982 में दक्षिण एशिया के देशों के लिए चिननी आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में

जो आक्रमण हुआ है, ईरान में जो गड़बड़ हो रही है और हिन्द महासागर में सोवियत संघ की जो बढ़ती हुई उपस्थिति है उसको देखते हुए दक्षिण एशिया के देशों के साथ हमारे सम्बन्धों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। इन गतिविधियों ने इस क्षेत्र को जो हम महत्व देते हैं उसे बढ़ा दिया है। हम यह स्वीकार करते हैं कि यह उस क्षेत्र का दाहिना बाजू है जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के जीवन्त हितों को खतरा हो सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने प्रस्ताव किया कि पाकिस्तान को 5 करोड़ डॉलर पी. एल. 480 के अन्तर्गत और 17 लाख डॉलर अफगान शरणार्थियों के लिए दिए जाएं। यह धन इसलिए दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अधिक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी हो।

जब पाकिस्तान अधिक मजबूत होता है और उसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमें अच्छी तरह मालूम है। श्रीमती जैन ने सकेत दिया कि पाकिस्तान के लिए सहायता सीमित है और उसे बढ़ाने तथा पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को और दृढ़ करने पर हम विचार कर रहे हैं। बाद में समाचार यह आया है कि पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की अस्त्र सहायता देने तथा पाकिस्तान के साथ सैनिक-सन्धि करने का विचार चल रहा है।

श्रीलंका के लिए 10 करोड़ 33 लाख, बंगलादेश के लिए भी 10 करोड़ 33 लाख और नेपाल के लिए 1 करोड़ 82 लाख डॉलर की सहायता प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि हम भारत को 25 करोड़ 85 लाख डॉलर की सहायता देंगे जो भारत की दृष्टि से तो कम है परन्तु हम इससे अधिक दे नहीं सकते।

यह तो हुआ वह आँकड़ा जो सहायता के नाम पर भारत के इर्द-गिर्द फेंका जा रहा है। अब हम जरा समझें कि हिन्द महासागर में सैनिक स्थिति क्या है? सन् 1980 के प्रारम्भ में डियागो गार्सिया में 2000 अमेरिकी सैनिक थे और 400 सैनिक उज्जरी बरब में थे। फारत की खाड़ी में अमेरिका की एक नौ-सैनिक टुकड़ी थी जिसमें चार जगो जहाज थे, इसके अनिर्दिष्ट हिन्द महासागर में पाँचवाँ बड़ा था जिसमें दो विमानवाहक पोत, तीन सेना उतारने वाले जहाज और 16 जगो जहाज थे। इनके अनिर्दिष्ट हिन्द महासागर में अमेरिकी सैनिक भ्रष्टे भी थे। एक बड़ा थोमन राज्य के अन्तर्गत मसीरा टापू पर था, दूसरा मिस्र के सिनाई रेगिस्तान में था, तीसरा सोमालिया के बरबरा बन्दरगाह पर था और चौथा गीनिया की राजधानी नैरोबी के हवाई अड्डे पर और मोम्बासा बन्दरगाह पर। 5वें बड़े में उस समय कुल मिलाकर 16000 नाविक और तिपाही थे। सन् 1981 में इस स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ है।

सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह हुआ है जैसा कि श्रीलंका के समाचार-पत्र 'फारवर्ड' ने छापा है—डियागो गार्सिया में 19 नाविकीय (अणु बम या उद्भ्रम बम) की नौकें उतार दी गई हैं जो विमानों या मिसाइलों द्वारा किसी भी हिन्द महासागर स्थित देश तक पहुँचाई जा सकती हैं। डियागो गार्सिया की उड़न पट्टी के विकास पर

4 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया गया है जिससे कि वहाँ पर बी-52 प्रकार के अणुबम ले जाने वाले बमवर्षक उतर सकें। इस समय हिन्द महासागर में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के कुल मिलाकर 42 जमी जहाज हैं जिनमें 2 विमान वाहक पोत हैं, 3 क्रूजर हैं, 26 विध्वंसक और फिग्रेट हैं, 7 मिगाइल फेंकने वाले जहाज हैं, 2 पनडुब्बियाँ हैं और बमान जहाज हैं। अमेरिकी जहाजों के ऊपर 170 विमान हैं और इनमें 80 विमान ऐसे हैं जिनमें अणुबम या उद्‌जन बम रखे हुए हैं। इस प्रकार हिन्द महासागर में किसी भी क्षण आणविक युद्ध छिड़ सकता है।

कहने को तो यह कहा जा रहा है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है कि इस बात का खतरा है कि सोवियत संघ धीरे-धीरे अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते से बढ़कर अरब सागर और फारस की खाड़ी में स्थित तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को तबाह कर देगा। अमेरिका में एक ऐसी दुकड़ी का भी विकास किया जा रहा है जो किसी समय इस क्षेत्र में थल सेना के रूप में कही जाना सकती है और कहा जा रहा है कि उसका मुख्यालय ब्रिसेल्स में होगा और तंताती सिनाई प्रायद्वीप में। कैलिफोर्निया और एरीजोना में 7वीं लैंडिंग ब्रिगेड बड़े जोर-शोर से यह तैयारी कर रही है। अमेरिकी रक्षामन्त्री श्री वास्पर बेनबरगर ने अमेरिकी सीनेट के समक्ष जो बयान दिए हैं उनमें सोवियत संघ से होने वाले खतरो पर बहुत जोर दिया है। पर उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि यदि मध्य-पूर्व या दक्षिण एशिया के किसी देश में आन्तरिक उथल-पुथल होती है तो उसमें भी अमेरिकी हितों को खतरा हो सकता है। यह सभी जानते हैं कि अगर किसी कारणवश अमेरिका और रूस की टक्कर हो गई तो वह सीमित नहीं रहेगी। यदि हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा लेता है तो जिन क्षेत्रों में रूस अधिक शक्तिशाली कहा जाता है (यानी यूरोप में) वह वहाँ पर बढ़ला लेगा और यह युद्ध हिन्द महासागर का सीमित युद्ध न रहकर विश्व-युद्ध हो जाएगा। विश्वयुद्ध के लिए बावजूद सारी विल्लपो के न अमेरिका तैयार है और न रूस। यूरोप में अमेरिका के जितने साथी हैं चाहे जर्मनी हो या फ्रांस, वे भी तीसरा विश्वयुद्ध नहीं चाहते। वे तो यह भी नहीं समझ सकते कि अमेरिका पश्चिमी यूरोप में कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसमें रूस भड़के। इसका सीधा-सादा अर्थ यह है कि अमेरिका द्वारा हिन्द महासागर में और पश्चिम एशिया तथा दक्षिण एशिया में जो भी तैयारी की जा रही है उसका उद्देश्य इस क्षेत्र के देशों को घमकाकर रखना है जिससे वे कोई ऐसी कार्यवाही न करें जो अमेरिकी हितों के विनाश हो।

इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अमेरिकी हित तो यह है कि जो पाँच बहुराष्ट्रीय तेल कम्पनियाँ अमेरिका की हैं उनका मुनाफा बढ़तूर रहे। अमेरिका में आधुनिक पाँच और ब्रिटेन में आधारित दो, सान तेल् कम्पनियाँ सान बहने कहलानी हैं। इनके नाम हैं एक्मोन, रायन, डचशेल, मोबिल/टैक्साको, ब्रिटिश पेट्रोब्रियम, स्टैण्डर्ड ऑयल ऑफ कैलीफोर्निया तथा गल्फ। 1979 में इन सात बहनों द्वारा जो मुनाफा कमाया गया वह 20 अरब डॉलर से अधिक था और 1978 की तुलना में उसमें 94%

की वृद्धि हुई। इस मुनाफे में 90% मुनाफा मध्य-पूर्व के तेल व्यापार से प्राप्त हुआ। 1979 में इन कम्पनियों ने कुल 91 करोड़ टन तेल खरीदा था जिनमें से 57 करोड़ 20 लाख टन तेल फारस की खाड़ी के देशों से खरीदा गया था। यह तेल पश्चिमी यूरोपीय देशों की कुल आवश्यकता का 68% और जापान की तेल आवश्यकता का 80% होता है। इस प्रकार मुख्य उद्देश्य यह है कि इन क्षेत्रों से जो कमाई होती है वह होती रहे और कोई देश इस हालत में न हो कि विदेशी कम्पनियों की इस नफाखोरी को कम कर सके। साथ ही इस क्षेत्र में तनाव होने से अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय कम्पनियों के हथियार बनाने के धन्धे को लाभ होता है। एक तरफ पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के व्यापारी भारत की ओर दौड़ रहे हैं कि वह हथियार खरीदे। नतीजा यह है कि इस तनाव से और यदि युद्ध हो जाए तो युद्ध से पश्चिमी कम्पनियों को ही लाभ है, पश्चिमी शक्तियों को ही लाभ है और जो फौजी तैयारियाँ हो रही हैं वे कमजोर राष्ट्रों को दबाने के ही काम में आएँगी, रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र से सड़ने के लिए नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ अन्य पहलू और नवीन घटना-चक्र (Some Other Aspects and New Developments of International Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना-चक्र एक अविराम प्रवाहमान सरिता की भाँति है जिसमें नित-नए परिवर्तनों के छोटे-मोटे बुलबुले उठते-गिरते रहते हैं, परिवर्तनों की लहरें हिलोरे मारती रहती हैं। कुछ परिवर्तन अपेक्षाकृत ज्ञान प्रकृति के होते हैं तो कुछ काफी उग्र और विस्फोटक। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न मैकानिक और व्यावहारिक पहलुओं, महाशक्तियों की विदेश-नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघ, निःशस्त्रीकरण, शीतयुद्ध आदि का विस्तार से उल्लेख पूर्ववर्ती अध्यायों में किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में पुस्तक के समापन के रूप में हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ अन्य उल्लेखनीय पहलुओं, नवीन घटना-चक्रों तथा दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करेंगे।

डियागो गार्सिया : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का

एक नया विस्फोटक केन्द्र

लागोन द्वीपसमूह में 7 डिग्री 18 अंश दक्षिणी अक्षांश एवं 72 डिग्री शून्य अंश पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित डियागो गार्सिया एक सुदृढ़ और मजबूत द्वीप है। भारत के कन्याकुमारी से नीचे दक्षिण में इसकी दूरी लगभग 1130 मील है, मारिशस से इसकी दूरी पूर्व की ओर लगभग 500 मील है, यहाँ से सिंगापुर 2560 मील, अदन 2670 मील, फ्रान्सेलिया (पर्व) 3400 मील, ईराक बिर्तु'क 3800 मील, ईराक (कर्मन्गाह) 400 मील, कुवैन 3500 मील तथा कातार 2000 मील दूर है। यह द्वीप हिन्द महासागर के ठीक बीचोबीच स्थित है। यह द्वीप मूलतः मारिशस राज्य का एक भाग था। अंग्रेजों ने जब मारिशस को आजाद किया, तब इस द्वीप की संचार-साधनों की सुविधा के लिए अपने पाय रखा गया। बाद में मई 1965 में ब्रिटेन ने मेडगास्कर के उत्तर में परकुदूर से चालीस के दक्षिण में हेगरोचक्र के पाँच टापुओं, जिनमें डियागो गार्सिया प्रमुख है, को मिलाकर एक नया उपनिवेश बनाया। इसका नाम 'ब्रिटिश इण्डियन ओशन टैरीटरीज' रखा गया। 18 अगस्त, 1967 को इन्हें ब्रिटेन ने मारिशस से 10,13,200 पौण्ड में तरीद

लिया। सामरिक दृष्टि से डियागो गार्सिया की भौगोलिक स्थिति हिन्द महासागर में काफी प्रभावशाली है। आज अमेरिका इस द्वीप को एक सुदृढ़ सामरिक सैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना चुका है। 1974 में ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार ने अमेरिका को यहाँ सामरिक अड्डा बनाने की अनुमति दे दी थी। यह सुनकर कितना अजीब लगता है कि ब्रिटेन की मजदूर-दलीय सरकार ने यहाँ मचार-साधनों के लिए अड्डा स्थापित करने का अमेरिका से समझौता किया और सामरिक सैनिक अड्डे के रूप में उसे परिवर्तित करने के लिए अमेरिका को सुविधा देने का फैसला भी मजदूर-दलीय सरकार ने ही किया।

डियागो गार्सिया अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विस्फोट का एक शक्तिशाली केन्द्र बन गया है। अमेरिका इस द्वीप को एक सुदृढ़ सामरिक सैनिक अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। यह द्वीप हिन्दमहासागर के तटीय देशों के लिए खतरे का एक आधार बनेगा क्योंकि यहाँ अमेरिका की उपस्थिति अन्य महाशक्तियों को आने और अपने-अपने सैनिक अड्डे बनाने का निमन्त्रण देगी। इनमें सोवियत रूस और साम्यवादी चीन प्रमुख हैं। डियागो गार्सिया के सैनिक अड्डे पर अमेरिका प्रक्षेपणास्त्रों से युक्त जहाज तैनात कर रहा है जिनकी मार की परिधि में लगभग सभी तटवर्ती देश और अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीपों के अन्दर के देश भी आ जाते हैं। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र में तनाव और खतरे का वातावरण तो बनेगा ही, साथ ही यहाँ राजनीतिक आर्थिक, सैनिक घुसपैठ और धोसपट्टी भी प्रारम्भ होगी।

प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने हिन्द महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा परमाणु-अड्डा कायम करने के निर्णय की भर्त्सना की है और इसे शान्ति के लिए एक खतरा बताया है। श्रीमती गांधी ने कहा है कि हिन्द महासागर में परमाणु-अड्डा कायम करने का निर्णय समुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव के विरुद्ध है और इससे तनाव में वृद्धि होगी। हिन्दमहासागर में जो स्थिति बन रही है उसको देखते हुए अपने सम्बन्ध समुद्री तट के कारण अपनी सुरक्षा के बारे में भारत का चिन्तित होना स्वाभाविक है। भारत ने लगातार मांग की है कि हिन्दमहासागर क्षेत्र को बड़े राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखना चाहिए। उसे विदेशी अड्डों और परमाणु-अस्त्रों से भी अछूता रखना चाहिए।

पश्चिमी जर्मनी-पोलैण्ड समझौता, मार्च 1977

12 मार्च, 1976 को पश्चिमी-जर्मनी के उच्च सदन बुण्डेस्टाट ने भारी रस्ताकशी के बाद जर्मनी और पोलैण्ड में पेन्शन समझौते हुए और उससे सम्बद्ध दोनों गन्धियों का अनुमोदन कर दिया। इस समझौते पर 9 अक्टूबर, 1975 को वार्सा में दोनों देशों के विदेश मंत्री हस्ताक्षर कर चुके थे। समझौते के अनुसार पश्चिमी जर्मनी ने पोलैण्ड को युद्ध पीड़ितों की पेन्शन के लिए 12 लाख जर्मन मार्क तथा नाममात्र के व्याज पर एक दीर्घवधि ऋण देना स्वीकार किया और बदले में पोलैण्ड ने वचन दिया कि आगामी चार वर्षों में वह पोलैण्ड में रहने वाले जर्मन नागरिकों में से लाख, राबो लाख के करीब जर्मनों को पश्चिमी जर्मनी में वापस जाने की अनुमति

दे देगा। पोलैण्ड ने आश्वासन दिया कि बाद में अन्य लोग भी जर्मनी जाने का आवेदन-पत्र भर सकेंगे और उन्हें भी अनुमति दी जाएगी।

बीस वर्ष पहले नाज़ियो ने पोलैण्ड के लोगों पर जो जुल्म ढाए थे, उन्हें भुलाकर पोलैण्ड ने मंत्री का जो हाथ बड़ाया है उसके मूल में शावद आर्थिक और व्यापारिक कारण भी रहे हों पर सच्चाई यह है कि 1970 में भूतपूर्व जर्मन चांसलर विली ब्रॉट ने पूर्वी यूरोप के देशों से सम्बन्ध सामान्य बनाने की जिस नीति का सूत्रपात किया था यह समझौता उसी का चरमोत्कर्ष है।

अफगानिस्तान में क्रांति (1979) रूसी हस्तक्षेप

27 दिसम्बर, 1979 को एक बार फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सड़कों पर टैंक देखे गए। 6 सितम्बर, 1979 को सत्ता रुड़ हुए राष्ट्रपति हफीजुल्ला अमीन का तख्ता पलट दिया गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति नूर मोहम्मद ताराकी (प्रबुद्धिमत) के उप-राष्ट्रपति दबराक कारमाल ने इस बार तख्ता पलटा था। सफल क्रांति के बाद उन्होंने रेडियो से घोषणा की कि वह देश को स्वच्छ शासन देये। स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्होंने सोवियत सघ से राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और सैनिक सहायता की माँग की जो उन्हें तुरन्त प्रदान की गई।

अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति के मुद्दे पर संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भी काफी लम्बी बहस हुई। इस बहस में अफगानिस्तान के विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद दोस्त ने रूसी सहायता का समर्थन करते हुए कहा कि रूसी सैनिक हमारे आग्रह पर ही काबुल आए थे। पिछले 13 वर्षों में सुरक्षा परिषद् का यह छठा आपात्कालीन अधिवेशन था। इससे पहले तीन अधिवेशन पश्चिमेशिया की स्थिति पर, एक 1956 में हंगरी की समस्याओं पर तथा 1960 में कोणो की समस्याओं पर हो चुका है। अफगानिस्तान के विदेश मन्त्री ने अपने देश की स्थिति को आन्तरिक मामला बताया और यह भी कहा कि इससे उस क्षेत्र की शांति को किसी प्रकार का खतरा नहीं। उनका यह भी तर्क था कि प्रत्येक देश को 'आत्मरक्षा' का अधिकार है और उसके लिए वे किसी भी तरह की बाहरी सहायता का पूर्ण अधिकार रखते हैं। उनका यह भी मानना था कि अफगानिस्तान अपने प्रापको 'साम्राज्यवादी' शक्तियों से सोवियत सघ की सहायता से भ्रमण कर रहा है। ज्यों ही उसकी स्थिति 'मजबूत' हो जाएगी, सोवियत सेनाएँ वहाँ से हट जाएँगी। इसी आशय का एव पत्र सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझेनेव ने भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गान्धी को लिखकर उन्हें आश्वासन दिलाया था कि सोवियत सेना अफगान सरकार के आग्रह पर तुरन्त वहाँ से हट जाएगी। लेकिन चीन का आरोप था कि सोवियत सैनिकों को अफगान सरकार ने नहीं बुलाया था बल्कि उनका यह प्रपना निमन्त्रण था। इस तरह के विचार का कोई आधार नहीं कि अफीजुल्ला अमीन अपने पतन के लिए सोवियत सघ को निमन्त्रित करते। चीनी प्रतिनिधि चेङ्ग चू ने सोवियत कायेंवाही को तामसी दुनिया के देशों सोवियत में विस्तार की गतिविधियाँ करार दिया। यह वैकन अफगानिस्तान तक

ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी लम्बी बहस के बाद सुरक्षा परिषद् ने सोवियत संघ से अफ़ग़ानिस्तान में अपनी गतिविधियाँ समाप्त करते हुए सैनिकों की वापसी का प्रस्ताव पास किया लेकिन इस प्रस्ताव पर सोवियत संघ ने अपने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को नाकाम कर दिया।

असन्तुष्ट अफ़ग़ानों की विद्रोही कार्यवाहियों के बावजूद अफ़ग़ानिस्तान के भीतर सोवियत सैनिक अपना नियन्त्रण निरन्तर मजबूत करते गये। अप्रैल, 1980 में अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत सेनाओं के रहने पर सोवियत मंच और अफ़ग़ान सरकार में एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। 20 नवम्बर, 1980 को संयुक्तराष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मांग की गई कि सोवियत मंच अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेनाएँ वापिस हटा ले लेकिन महासभा का प्रस्ताव केवल कागजी सिद्ध हुआ। 6 फरवरी, 1981 को अफ़ग़ानिस्तान ने यद्यपि राष्ट्रसंघ की गण्यस्थता स्वीकार कर ली तथापि 21 फरवरी, 1981 को अफ़ग़ान राष्ट्रपति बबराक कारमाल ने स्पष्ट कर दिया कि अमरीकी षड्यन्त्रों के कारण सोवियत सैनिकों का अफ़ग़ानिस्तान में प्रवेश आवश्यक था और वर्तमान परिस्थितियों में वहाँ सोवियत सैनिकों का बने रहना जरूरी है। अप्रैल, 1981 में अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत सैनिकों की संख्या और अधिक बढ़ाई गई। अगस्त, 1981 में लगभग 80 हजार रूसी सैनिक अफ़ग़ानिस्तान में तैनात थे।

अफ़ग़ानिस्तान की समस्या अभी (मार्च, 1982) यथापूर्व है सिवाय इसके कि इन सम्बन्ध में अमेरिका तथा उसके साथी राष्ट्रों का विरोध अब उष्ण पड़ता जा रहा है। अफ़ग़ानिस्तान के भीतर सोवियत सैनिक अपना नियन्त्रण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी समरनीति तय की है। ऊपर विद्रोही अफ़ग़ान सोवियत सैनिकों को घुरी नरह परेशान कर रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत सैनिकों की वापसी को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव निरन्तर बढ़ रहा है। केवल अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश ही सोवियत संघ से अफ़ग़ानिस्तान को हटाने के लिए जोर नहीं डाल रहे हैं बल्कि अरब, एशिया, अफ्रीका आदि देशों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सोवियत रूस ने सकेत दिया है कि यदि अफ़ग़ान सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा तथा बाह्य शक्तियों का अफ़ग़ानिस्तान पर दबाव हट जाएगा तो उसका अफ़ग़ानिस्तान में बने रहने का कोई इरादा नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का नया सितारा इस्लाम¹

ईरान की शान्ति के बाद अन्य मुस्लिम देशों में भी इस्लाम के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित राज्य-व्यवस्था स्थापित करने का जो पुरजोर प्रयास शुरू हुआ है, उससे राष्ट्रों की विरादरी में बहुत सारी आशाएँ उठ खड़ी हुई हैं। सार्वभौमिक इस्लामी बन्धुत्व और इस्लाम के मूल तत्त्वों के आधार पर शासनतन्त्र

के संचालन का सिद्धान्त आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील राजनीतिक विचारधाराओं के लिए एक सशक्त चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। जिन देशों में राजसत्ता का चरित्र धोषित संबंधानिक तौर पर इस्लामी है, वहाँ भी उपपन्थी धार्मिक पुनरुत्थानवादियों एवं प्रगतिशील आधुनिक विचारों में आस्था रखने वाले तत्त्वों के बीच एक निरन्तर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या धर्म की बुनियादी पुरातन मान्यताएँ आधुनिक औद्योगिक समाज और राज्य की आधारशिला बन सकती हैं? क्या स्वतन्त्र राज्यों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध धार्मिक आधार पर निर्धारित होना उचित है? ऐसे सवालों पर बहस चलनी जरूरी है, पर उससे भी कहीं अधिक जरूरी यह जानना हो जाता है कि इस्लाम का पुनरुत्थान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किन परिस्थितियों और दबावों के चलते हुए सम्भव हुआ है और अनेक-जातीय, अनेक भाषायी तथा एक से अधिक धर्मों वाले आधुनिक राज्यों की क्षेत्रीय अखण्डता और भावनात्मक एकता को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है?

बैसे तो भारत-विभाजन के समय भी द्वि-राष्ट्रवाद का सिद्धान्त प्रतिपादन कर यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र के रूप में ही रह सकते हैं और धर्म ही राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा आधार है, किन्तु 1971 में बंगलादेश का निर्माण तथा 1947 के बाद से लगातार भारत के सामाजिक-राजनीतिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को मानते हुए सभी धर्मों के मानने वालों की सक्रिय हिस्सेदारी इस बात का प्रमाण है कि केवल धार्मिक विश्वास व्यक्तियों या राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों का कारण नहीं बन सकते। यदि ऐसा होता तो मलयेशिया और इण्डोनेशिया के बीच 1963-65 तथा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच 1970-71 में सशस्त्र संघर्ष की नीबट न आती।

धर्म और राष्ट्रों की विरादरी

पर धर्म के आधार पर राष्ट्रों की विरादरी मनाने की कोशिश और उसमें नाकी हूब तक सफलता हमारे समय की सच्चाई है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अपने अस्तित्व में आने के तुरन्त बाद के वर्षों में पाकिस्तान ने इस्लामी विरादरी की स्थापना के प्रयास में कराँची में एक सम्मेलन किया था, जिसे अमेरिका का परीक्ष समर्थन प्राप्त था, पर सोवियत संघ ने उस सम्मेलन की नीयत पर गंका व्यक्त करते हुए उसकी कड़ी आलोचना की थी। चूंकि भारत उस समय गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की विरादरी का मुखर प्रवक्ता बन चुका था और मार्च, 1947 में ही दिल्ली में 'एशियन रिलीजन्स कान्फ्रेंस' आयोजित कर चुका था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि पाकिस्तान एक समानान्तर मंच तैयार कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को स्थापित करने का प्रयास करना एवं इस्लामी विरादरी को एजेंडु कर पाना उस समय ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि नवीदित मुस्लिम राष्ट्र तब तक अपने प्रांति, सामाजिक हितों की ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रों के साथ समान गन्धन्ध बनाए

रखना उचित समझते थे। इनके अलावा मिस्र, इण्डोनेशिया—जैसे प्रभावशाली इस्लामी देश गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मंच को विकासशील देशों के लिए राजनीतिक, आर्थिक कारणों से ज्यादा कारगर मानते थे।

वैचारिक आधार मिला

साठवें दशक में पहुँचने के बाद ही इस्लामी विश्व-बन्धुत्व की धारणा को वैचारिक आधार मिला, जिसका एक प्रमुख कारण इजरायल द्वारा समूचे अरब विश्व की सुरक्षा के लिए चुनौती बन जाना भी था। 1948 में इजरायल के विरुद्ध अरब देशों को पहली लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 1956 में स्वेज नहर पर इजरायली आक्रमण के समय दूसरा युद्ध मिस्र को लड़ना पड़ा था। इजरायल की आधिपत्य, सामरिक और तकनीकी श्रेष्ठता का मुकाबला करने के लिए अरब देशों ने एक संयुक्त मोर्चा इस्लामी विरादरी के रूप में बनाया था और 1967 के तृतीय तथा 1973 के चतुर्थ अरब-इजरायल युद्ध के दौरान यह एकता और भी मजबूत हुई।

1967 में पहली बार तेल-उत्पादक अरब देशों ने इजरायल को समर्थन देने वाले पश्चिमी राष्ट्रों को तेल की सप्लाई बन्द कर देने की धमकी दी थी और 1973 में तेल की सप्लाई बन्द भी कर दी। यही से विश्व-राजनीति में तेल-राजनय की गुरुभात हुई। साथ ही साथ अरब राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग और सहृदयवाद (जिम्नोटिज्म) के खिलाफ एकता की जड़ें भी मजबूत हुईं।

सामूहिक प्रयास की महत्ता

1967 में इजरायल के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकने के प्रयास में मिली सफलता से अरब देशों को यह सीख मिली कि छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर देश भी सम्मिलित प्रयास से अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शक्ति के लिए मान्यता भी पा सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में 1969 में रवात में हुए पहले 'बृहत्तर इस्लामी' सम्मेलन के आयोजन और उसमें गठित इस्लामी सचिवालय के महत्त्व को समझा जा सकता है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि भारत ने भी रवात-सम्मेलन में इस आधार पर हिस्सा लेने की भरपूर कोशिश की थी कि भारत उन समय मुस्लिम आबादी की दृष्टि से तीसरे नम्बर का देश था, जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, किन्तु भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को रवात सम्मेलन से बहुत वेशावरू होकर वापस लौटना पड़ा था। दूसरे इस्लामी देश केवल मुस्लिम आबादी की बहुलता के आधार पर भारत को इस्लामी विरादरी में शामिल करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घोषित तौर पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।

रवात-सम्मेलन में जिस इस्लामी सचिवालय के गठन का निर्णय लिया गया था, उसका मुख्यालय रियाद में है। इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 43 है। राजदूतों तथा विदेशमन्त्री स्तर की इन देशों की आपसी बैठकें विभिन्न इस्लामी देशों की राजधानियों में अवसर लगभग हर साल होती रहती है, किन्तु शासनाध्यक्षों के स्तर

के शिखर-सम्मेलन अभी तक केवल 1969 में रवात तथा 1974 में पाकिस्तान में हुए हैं।

मुस्लिम अल्पसंख्यकों से चिन्ता

मई 1979 में लन्दन में इस्लामी देशों का एक सम्मेलन सम्पन्न हुआ था, जिसमें 27 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि दुनिया के जिन-जिन देशों में मुस्लिम जनसंख्या अल्पमत में होने के बावजूद कुछ विशेष क्षेत्रों या प्रान्तों में महत्वपूर्ण स्थिति में है, वहाँ-वहाँ उन्हें मुक्त कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रमुख विदेशी समाचार-पत्रों की रपट के अनुसार दक्षिणी फिलीपीन्स के मिण्डनाघो प्रदेश और भारत के जम्मू-कश्मीर प्रदेश का उल्लेख इस सिलसिले में किया गया, जिन्हें स्वाधीन कराए जाने की जिम्मेदारी इस्लामी देश महसूस करते हैं। स्वाभाविक ही है कि इस तरह के निर्णयों से उन सभी देशों को चिन्ता होगी, जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा इस्लामी-सम्मेलन द्वारा लिए गए इस प्रकार के बिबादास्पद निर्णयों से बहुजातीय, बहुराष्ट्रीय राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय में सन्देह और शका की भावना बढ़ने की भी सम्भावना बनती है।

दुनिया के जिन देशों में शासकीय स्तर पर राज्य व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है, पर जहाँ इस्लाम मतावलम्बियों की संख्या अल्पमत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण है, उनमें भारत, सोवियत संघ तथा चीन प्रमुख हैं। लन्दन-सम्मेलन में इन सभी देशों की आन्तरिक राजनीति में तनाव की स्थिति बन सकती है, परन्तु यह आशा की जानी चाहिए कि धर्म को राज्य का नियामक तत्त्व न मानने वाले राष्ट्र इस प्रकार के निर्णयों को गम्भीरता से नहीं लेंगे।

मोरक्को के राजदूत का वक्तव्य

इसी सन्दर्भ में भारत स्थित मोरक्को के राजदूत द्वारा भारत में अरब देशों के तरह राजदूतों के प्रवक्ता की हैसियत से भारतीय मुसलमानों की दशा पर दिया गया वक्तव्य भी समझना चाहिए। भारतीय मुसलमान देश की मुख्य सामाजिक राजनीतिक धारा के महत्वपूर्ण अंग हैं और पिछले 32 वर्षों में वे देश के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। मोरक्को के राजदूत का वक्तव्य न केवल भारतरत्नपूर्ण था, बल्कि उस संकीर्ण मानसिकता का परिचायक भी था, जो राजनीति को धर्म की तराजू पर तोल कर अपना उत्तुंगीकरण करना चाहती है।

दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस्लामी विरादरी का एक दबाव समूह के रूप में अशुभ पश्चिमी देशों की उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी राजनीति के विरोध के रूप में हुआ था। इसके अलावा पश्चिमी संस्कृति के सार्वभौमिक विस्तार और उसके परिणामस्वरूप एशियाई धर्मों की देशों के सामाजिक जीवन में आई विसंगतियों के प्रति विक्षोभ भी इस्लामी एकता का महत्वपूर्ण कारण था। पश्चिमी संस्कृति के गहनप्राही प्रभाव से पूर्व के देशों के पारस्परिक जीवन,

पुरातन सामाजिक ढाँचे और नैतिक आचार-विचार का समूचा तन्त्र चरमरा गया था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पा चुकने के बाद यह जरूरी और स्वाभाविक था कि नए स्वाधीन देश अपनी जातीय जड़ों और प्राचीन संस्कृति के उत्थ को तलाश करने की कोशिश में अपनी परम्पराओं के सन्दर्भ में कुछ नए जीवन-मूल्य गढ़ते। इस्लाम का पुनरुत्थान इस अर्थ में पश्चिमी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुत्व के खिलाफ अराहमति और विरोध का स्वर था, परन्तु इस्लामी विश्व के कुछ महत्वाकांक्षी शासक अपने को स्थापित करने के चक्कर में इस्लामी विरादरी के सब की सम्मिलित शक्ति का दुरुपयोग गैर-जिम्मेदाराना ढंग से करने के प्रयास में लगे हैं।

इस्लामी विरादरी की भावना

कुछ वर्ष पहले फिलीपीन्स के दक्षिणी हिस्से में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त में पुषकृतावादी आन्दोलन छिड़ा और लीविया के शासनाध्यक्ष कर्नेस गदाफी ने तुरन्त ही विशोहियों को शह देनी शुरू की थी। उगान्डा के अपदस्थ शासनाध्यक्ष ईदो अमीन अन्तर ही जलजलूत बलात्कार देने के आदी थे। पाकिस्तान-बंगलादेश युद्ध के दौरान भी अधिकतर मुस्लिम शासनाध्यक्षों की हमदर्दी पाकिस्तान के साथ थी। इस्लामी विरादरी की भावना अगर इस्लामी देशों को आर्थिक गैरबराबरी दूर करने और किसी सम्भावित बाह्य आक्रमण के खिलाफ रक्षापक्ति बनाने में सहायक होती है, तो निस्सन्देह एक अच्छी बात है, पर यदि इस्लामी विरादरी कुछ महत्वाकांक्षी राजनेताओं की सनक के कारण दूसरे देशों के अन्दरूनी मामलों में दखलन्दाजी को बढ़ावा देने का माध्यम बन जाती है तो संपुक्त रूप से सभी शान्तिप्रिय देशों द्वारा उसका विरोध किया जाना जरूरी है।

इसी सन्दर्भ में इस्लामी देशों में इस्लाम के बुनियादी मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रयास भी पश्चिमी देशों की नींद हराम किए हुए है। इस्लाम की आदिम, मध्ययुगीन मान्यताओं की स्थापना के प्रयास का विरोध इस्लामी देशों के प्रगतिशील आधुनिक विचारों वाले तत्त्वों द्वारा किया ही जा रहा है। ईरान, पाकिस्तान या कुवैत में रुढ़िवादी तत्त्वों का सत्ता में आ जाना कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं है, क्योंकि औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण और प्रगतिशीलता की बात करने वाले शासकवर्ग ने इन देशों में जिस तरह की अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापित कर दी थी, उसका पतन तो कभी न कभी होना ही था और यह आशा की जानी चाहिए कि इन देशों का जन सामान्य धार्मिक कट्टरता के नाम पर उठाए जाने वाले गैर-लोकतान्त्रिक कदमों का विरोध भी पूरी ताकत के साथ बरेगा।

आक्रामक शैली

किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रुढ़िवादी इस्लामी शासक वर्ग देश में अपने लिए विश्वसनीयता का वातावरण बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आक्रामक शैली अपना कर इस्लामी विश्व का नेतृत्व प्राप्त करने का

प्रयास कर सकते हैं। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का इस्तेमाल पहले भी होना रहा है और ईरान तथा पाकिस्तान के उदाहरणों में धर्म राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने की छील के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लाम के बुनियादी उमूलों की चिन्ता जनरल जिया-उल-हक को किस हद तक है, यह कहना तो मुश्किल है, पर यह साफ जाहिर है कि वे धर्मभिरु जनता की भावनाओं को उभार कर अपनी गद्दी बनाए हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी विरादरी

पिछले दस वर्षों में इस्लामी देशों में कट्टरपन्थी तत्त्व सक्रिय हुए हैं और इस्लामी विरादरी की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका निर्धारित करने में भी मुख्य योगदान मऊदी अरब जैसे रुढ़िवादी देशों का है। इन दिनों पाकिस्तान में 'जमायते इस्लामी', मिश्र में 'मुस्लिम ब्रदरहुड', मलेशिया में 'दाकवाँ'—जैसे कट्टरपन्थी इस्लामी समूहों का असर बढ रहा है। अफगानिस्तान में भी तराकी-शासन के खिलाफ सक्रिय गुट रुढ़िपन्थियों का ही है। काहिरा के रुढ़िवादी मुस्लिम पत्र 'अल दावाह' ने ईरान की क्रांति के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा था कि 'यहूदियों की चालाकी, ईसाइयों की घृणा और साम्यवादियों के आतंक के बावजूद मुस्लिम सत्ता में आते जा रहे हैं।' पाकिस्तान और कूबंत में भी ईरान की भांति ही न्याय व्यवस्था को शरीयत के अनुरूप ढाला जा रहा है। मिश्र की संसद् भी शरीयत को लागू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत सारे शराबघर, रात्रि क्लब और जुए के गड्डे बन्द कर दिए जाएंगे। उग्रपन्थी इम्नाम के पुनर्स्थापन का मापदण्ड यह भी माना जा सकता है कि हज जाने वालों की संख्या में 1974 से लगातार बढ़ोतरी होती गई है और नवम्बर, 1978 में 20 लाख तीर्थ यात्री हज करने गए थे। मस्जिद जाने की प्रवृत्ति में भी पिछले पाँच-सात वर्षों में वृद्धि हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस्लाम को एक प्रमुख तत्त्व के रूप में मान्यता जिन कारणों से मिली है, उनमें अफ्रीकी राजनीति में धार्मिक विश्वास का अम्मुदय, अरब देशों की तेल के कारण समृद्धि और ईरान की क्रांति प्रमुख हैं।

राजनीति के प्रति इस्लाम का रवैया मूलतः लोकतान्त्रिक है, क्योंकि उसमें ईश्वर के नामने मनुष्य मात्र की बराबरी पर जोर दिया जाता है। इस्लाम राज्य को व्यक्ति के रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम की आर्थिक धारणा पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के ही पक्ष में इस्तेमाल की जा सकती है।

यह उल्लेखनीय है कि कुछ मुस्लिम देशों में 2.5% गाराना कर हर व्यक्ति की सम्पत्ति पर मार्बजनिक्त कन्पाण के लिए धन प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। जगत के सभी सिद्धान्त की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करते हुए मऊदी अरब अपनी गाराना राष्ट्रीय आय का 7% अमेरिका, यू.एस. और मुस्लिम देशों को दान और वर्र के रूप में देता है।

मुस्लिम विद्वानों का मत है कि इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है जो तकनीकी और औद्योगिक विकास के विरोध में जाती हो। उन्हें केवल आधुनिकता के साथ जुड़ी विकृतियों से एतराज है, आधुनिकता या औद्योगीकरण से नहीं।

मलेशिया के इस्लामी युवा आन्दोलन के अध्यक्ष अनवर इब्राहीम के अनुसार “यदि आधुनिकता का मतलब शराब के कारखाने खोलना है, तो हम उसके विरोधी हैं, पर यदि आधुनिकता का मतलब इलेक्ट्रोनिक्स कारखानों से है, तो हम उसके पक्ष में हैं।”

कुन बिना कर राज इस्लामी विश्व के देशों में आधुनिकता बनाम पुरातन-पण्यता के बीच कशमकश चल रही है, और चीन के मिक्सांग, रूस के ताशकन्द और फिलीपीन्स के मिण्डानाग्रो जैसे मुस्लिम बहुल प्रदेशों में मुस्लिमों के लिए अधिक अधिकारों की व्यवस्था करने का दबाव पड़ रहा है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सशक्त गुट के रूप में इस्लामी देश संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य मंचों पर अपनी बातें मनवा सकने के लिए दबाव डालने में सक्षम हुए हैं। पर इस्लाम की यह सम्मिलित शक्ति तभी तक कारगर रहेगी, जब तक वह दूसरे देशों के अन्दरूनी मामलों को हवा नहीं देती।

इस्लामी देशों का लन्दन सम्मेलन 1979 : नए सन्दर्भ में

फरवरी 1979 में इस्लामी देशों के प्रतिरक्षा और विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन लन्दन में हुआ जो अब तक के सम्मेलनों में अपने ढंग का अकेला सम्मेलन था। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था—प्रतिरक्षा और इस्लामी दुनिया। सम्मेलन में तय किया गया कि इस्लामी दुनिया की प्रतिरक्षा के लिए एक नए सैन्य-व्यूह के निर्माण की परम आवश्यकता है। सम्मेलन ने दुनिया के इस्लामी देशों और उनकी सरकारों से आग्रह किया कि—

(1) वे अपने-अपने दायरे के अन्दर नया इस्लामी समाज बनाएँ जो किसी भी प्रकार के अन्याय और शोषण से परे हो और जिसमें पवित्र कुरान और सुन्नाह के नियमों का परिपालन किया जाए।

(2) अपनी वैचारिक स्वच्छन्दता और अपने देश की स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए प्रयत्न किए जाएँ और विदेशों द्वारा बलात् हड़पे गए अपने भू-भागों को पुनः प्राप्त किया जाए।

(3) अपनी और दुनिया की भलाई के लिए अपने ससाधनों का उपयोग किया जाए।

(4) राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपसी सम्बन्धों में निकटता लाई जाए और आपसी सहयोग के बल पर आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति में एक-दूसरे का हाथ बँटाया जाए।

सम्मेलन ने इस्लामी देशों से भी अनुरोध किया—

(1) प्रत्येक इस्लामी देश की सुरक्षा के लिए नि स्वार्थ रूप से ससाधनों का उपयोग किया जाए, ताकि दुनिया के सारे इस्लामी देशों की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति हो सके।

(2) ज्ञान के प्रसार और तकनालोंजी, शिक्षा और प्रशिक्षण में एक-दूसरे का सहयोग किया जाए।

(3) प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित रूप से उत्पादन के उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि सभी सामूहिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें।

इसके अलावा सम्मेलन ने ये भी सिफारिशें की—

(1) इस्लामी विशेषज्ञों का एक आयोग गठित किया जाए जो इस बात का पता लगा सके कि इस्लामी देशों में वैयक्तिक और सामूहिक सुरक्षा के लिए क्या कारगर उपाय हो सकते हैं।

(2) यह सस्वा इस्लामी देशों में ऐसे सम्मेलन आयोजित करे, जिनमें इस्लामी देशों की प्रतिरक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर विचार किया जा सके और इस मामले में उस देश की सरकार उसे पूरा सहयोग दे।

(3) इस्लामी देशों के प्रतिरक्षा, विज्ञान तथा तकनालोंजी के क्षेत्र में प्रगति करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाए तथा सस्ती दूरी पर रक्षा-उपकरण खरीदे जाएँ।

(4) इस्लामी देशों के विकास के लिए इस्लामी विशेषज्ञों के ज्ञान का समुचित उपयोग किया जाए।

(5) औद्योगिक और तकनीकी प्रायोजनाओं के नियोजन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

(6) इस्लामिक इन्स्टीट्यूट ऑफ डिफेंस का गठन किया जाए जो हर इस्लामी देश को प्रतिरक्षा सामग्री सप्लाई कर सके।

(7) इस्लामी विचारधारा की मुद्द और शान्तिकाल की माग्यनाओं का ज्ञान इस्लामी देश के हर छात्र को कराया जाए।

(8) इस्लाम की सुरक्षा से सम्बन्धित बातें पवित्र कुरान और सुन्नाह से ली जाएँ।

(9) इस्लामी मैन्य विद्या विशारदों की समिति का गठन किया जाए जो उपरोक्त तथ्यों को इस्लामी पद्धतियों के अनुरूप ढाल सकें और दूसरी अन्य बातों से उनके तादात्म्य को स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगा सके।

इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने सबसे अधिक सक्रिय भाग लिया। पाकिस्तान में जनरल जिया द्वारा शरिअत कानून लागू करने के मूल में इसी सम्मेलन की प्रेरणा रही है। सम्मेलन की समाप्ति के तुरन्त बाद ही पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मेजर जनरल सईद अली नवाब ने रेडियो प्रसारण द्वारा घोषणा की कि इस्लामिक बैंक ऑफ स्ट्रेटिजिक मैटीरियल्स की स्थापना के लिए पाकिस्तान ने 1000 लाख पौण्ड स्टर्लिंग सुरक्षित रख लिए हैं।

अपनी सैन्य-शक्ति को बढ़ाने और उममे कुशलता प्राप्त करने में आज पाकिस्तान इनका आगे बढ़ चुका है कि आबू धाबी की मुख्य हवाई शक्ति-32 मिराज

हवाई जहाजों पर पाकिस्तानी एयर फोर्स के पायलटों का ही आधिपत्य है। अकेले सकुदी अरब में प्रशिक्षणाधियों सहित रॉयल गाई के 5000 ट्रुप्स हैं जिनमें अधिकांश का नेतृत्व पाकिस्तानी करते हैं। लीबिया में लगभग 1450 पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग हैं। उसके चार मिराज स्वर्गार्डों में 50% पाकिस्तानी पायलट और तकनीशियन हैं। उसके 250 स्थल-सेना और 100 जल-सेना के अधिकारी भी पाकिस्तानी ही हैं। अम्मन के पास 100 पाकिस्तानी ट्रुप्स हैं। अरबों की सहायता के लिए पाकिस्तान ने अपने ट्रुप्स भेजे थे—यह सर्वविदित ही है। एक पश्चिमी पर्यवेक्षक के अनुसार 1973 के युद्ध में लीबिया और सीरिया की सहायता के लिए पाकिस्तान ने अपने पायलट भेजे थे। एक-दूसरे बयान के अनुसार सीरिया की सीमा पर पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने सक्रिय भाग लिया था।

स्टॉफ कॉलेज बवेटा में पाकिस्तान अपने मित्र अरब देशों के प्रशिक्षणाधियों को प्रशिक्षण देता है। मिराज ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें 10 मिराज, 3—डी एस. अरबों द्वारा गैर स्वरूप दिए गए हैं, सक्रिय रूप में कार्यरत हैं।

दिल्ली में राष्ट्रकुल का क्षेत्रीय सम्मेलन (सितम्बर 1980)

4-8 सितम्बर, 1980 को दिल्ली के विज्ञान भवन में एशियाई और प्रशान्त देशों के 16 राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का राष्ट्रकुल का दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कई प्रकार से महत्वपूर्ण था। 1978 में सिडनी में हुए पहले सम्मेलन की अपेक्षा इसमें कुछ देश अधिक शामिल हुए, जिन्हें 1979 और 1980 में स्वाधीनता प्राप्त हुई। इन छोटे देशों की भूमिका पर राष्ट्रपति नीलम सजीव रेड्डी ने अपने उद्घाटन भाषण में विशेष चर्चा की। पहले दिन ही इन छोटे देशों ने अपने भविष्य की भूमिका के बारे में जिन इच्छाओं की रेखांकित किया उससे लगता था कि वे न केवल राष्ट्रकुल को दृढ़ बनाने में ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे बल्कि एशियाई और प्रशान्त क्षेत्रों के विकास में भी उत्तेजनपूर्ण भूमिकाएँ निभायेंगे।

इस तरह के क्षेत्रीय सम्मेलनों का उद्देश्य परस्पर द्वि-पक्षीय सम्बन्धों को दृढ़ बनाना तो होता ही है, अपने क्षेत्र में एकता और अखण्डता की भावना को दृढ़ करना भी उनका दायित्व है। इन उद्देश्यों में सद्भाव की भावना का विकास करना, विभिन्न क्षेत्रों में सम्बन्ध स्थापित करना, व्यापार के क्षेत्र में प्राथमिकताएँ निश्चित करना, वैज्ञानिक और प्राविधि सम्बन्धी अनुभवों का आदान-प्रदान करना, औद्योगिक और प्रबन्ध सम्बन्धी क्षेत्रों में एक-दूसरे की सहायता करना आदि प्रमुख हैं। 1978 में इन्हीं विषयों को आधार बनाकर संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने पर बल दिया। दिल्ली सम्मेलन का स्वर भी सिडनी जैसा था। छोटे-बड़े सभी देशों का बिना भेदभाव एक मंच पर उपस्थित होना, परस्पर मतभेद का ही परिचायक था। एक छोटा सा देश नीरू है जिसकी आबादी मात्र साढ़े सात हजार है लेकिन सप्ताह में

प्रति व्यक्ति सबसे ऊँची आय वाला देश (नाडे बाईस हजार डालर)। इसके विपरीत भारत है जिसकी जनसंख्या 60 करोड़ के करीब है लेकिन प्रति व्यक्ति आय मात्र 160 डालर है। बंगलादेश में प्रति व्यक्ति आय 80 डालर है। आस्ट्रेलिया अपने आय में एक महाद्वीप है जो 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लेकिन उसकी आबादी केवल एक करोड़ 40 लाख ही है और प्रति व्यक्ति आय 7200 डालर है। इन सभी देशों की कुल जनसंख्या 70 करोड़ है जबकि सारे राष्ट्रकुल देशों की आबादी एक अरब से कुछ ही अधिक है। निस्संदेह इस तरह के मिले-जुले परिवार में जिस तरह की एकता की भावना होनी चाहिए उसको दृढ़ करने में इस तरह के सम्मेलन उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं।

इस सम्मेलन में भिन्न देशों और उनके प्रमुख नेताओं ने अपने देश का नेतृत्व किया उनमें 12 देशों के प्रधानमंत्री और चार देशों के राष्ट्रपति थे। भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। अन्य देश और उनके नेता इस प्रकार थे—आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माल्कम फ्रेजर, बंगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर्रहमान, फिजी के प्रधानमंत्री रातु सर कामिसेसे मारा, किरिबाती के राष्ट्रपति आयरेमारिया तावाई, मलेशिया के प्रधानमंत्री दातुक हुसैन आन, नौरु के राष्ट्रपति हैमर द राबर्ट, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री राबर्ट मान्डून, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री सर जुलियस चान, मिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ब्रान यू, सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री पीटर कंनिलोरिया, श्रीलंका के राष्ट्रपति जे. जयवर्द्धन, टोंगा के प्रधानमंत्री फातेफेही तू इपलेहो, तुवालू के प्रधानमंत्री तावोलिपि, वनूआतु के प्रधानमंत्री वाल्टर लीनी तथा पश्चिम समोआ के प्रधानमंत्री तुपुफाला ऐफी। सम्मेलन के अलावा इन देशों के नेताओं में अनौपचारिक तौर पर भी बानचीन हुई।

13-16 फरवरी, 1978 को सिडनी में हुए सम्मेलन में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशान्त महासागर, आतंकवाद पर अक्रुश, निःशस्त्रीकरण के प्रसार, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया आदि समस्याओं के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। इसके साथ ही क्षेत्रीय राष्ट्रकुल देशों द्वारा परस्पर मामान्य व्यापार नीति तथा औद्योगिक विकास पर बल देते हुए ऊर्जा की निरन्तर कमी में निपटने के लिए एबडी बंदम उठाने पर जोर दिया गया था। इन बंदमों में मानव स्रोतों के विकास, गैर-न्यूनी ढंग से बढ़ने वाले मादक वस्तुओं के फैलाव को रोकने पर भी जोर दिया गया था। छोटे देशों की समस्याओं को सही ढंग में सुलझाने के लिए एक विशेष मंच की स्थापना का अनुभव किया गया। इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि इन छोटे देशों के पास कच्चे माल की बहुलता का किस प्रकार से दस्तेमाल किया जा सकता है।

इस समय इस तरह के सम्मेलनों के आयोजन को लेकर तरह-तरह के प्रश्न किए गए। कुछ विशेषण-कर्ताओं का यह भी मानना था कि वर्तमान सम्मेलन का आयोजन भारत में जल्द हुआ है लेकिन उसका लाभ आस्ट्रेलिया को होने वाला है। यह भी कहा गया कि भारत के पड़ोसी देशों में मुख्यतः बंगलादेश और श्रीलंका भी आते हैं, जबकि अन्य सभी देश आस्ट्रेलिया के अधिक निकट हैं। यहाँ तक कि

मलेशिया और सिंगापुर भी अपने आपको भौगोलिक तौर पर आस्ट्रेलिया के अधिक नजदीक पाते हैं। 'एशियन' देशों का महत्वपूर्ण होने के नाते आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ इनका विशेष तालमेल है। प्रशान्त महासागर में स्थित छोटे देश भी आचार-व्यवहार तथा परम्पराओं के कारण अपने आप को आस्ट्रेलिया के अधिक पास पाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे आस्ट्रेलिया से हर तरह की सहायता की अपेक्षा भी कर सकते हैं। पातुआ और न्यूगिनी कभी आस्ट्रेलिया के ही भाग थे। वेशक अब वह स्वाधीन हो गया है लेकिन आस्ट्रेलिया का वर्चस्व वहाँ बना हुआ है।

आस्ट्रेलिया बड़ा देश है ही और उसे एकदेशीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तामुसकिन नहीं कि आस्ट्रेलिया नव-स्वाधीन छोटे-छोटे देशों जैसे तुवालु, वनुआतु सोलोमन द्वीपसमूह पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना हुआ उनके विकास-कार्य में योगदान दे। प्रशान्त सागर स्थित ये देश खनिज में खाते सम्पन्न हैं और उनके कच्चे माल के दोहन में आस्ट्रेलिया को यह सस्ता भी पड़ेगा और जल्द भी उपलब्ध हो सकेगा। उनके कच्चे माल के एवज में वह अपना माल बड़े पैमाने पर इन छोटे देशों में खपा कर अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत बना सकता है। इस व्यापारिक स्थिति द्वारा ही वह सरकार और लोगों के दिन में अपने लिए स्थान बना सकता है। समय-समय पर उनके द्वारा चाही गई आर्थिक और सामरिक सहायता भी देने की वह स्थिति में है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रशान्त के इन छोटे देशों को धलग-धलग समूहों में गठित करने की आस्ट्रेलिया की एक दूरगामी योजना है। यदि यह योजना कार्यान्वित होती है तो बेरमवेर इसका पैता हो स्वरूप होगा जैसा अमेरिका का पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ है या सोवियत मध्य और पूर्व यूरोप के देशों के बीच है। माल्कम फ़ोर्जर आस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर इसलिए जोर दे रहे हैं।

भारत के राष्ट्रपति श्री नीलम सजीव रेड्डी ने कहा कि भारत ने राष्ट्रमण्डल के स्वरूप का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमण्डल हम सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर हम इसके गतिशील ढाँचे की उन्नत क्षमता का उपयोग बेहतर उद्देश्य के लिए करें। इस सम्मेलन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह कार्यात्मक सहयोग की व्यवस्था में कितनी जीवन्त-शक्ति का संचार कर सकता है। इस सम्मेलन से सदस्य देशों के बीच और अधिक सहयोग के लिए सम्भावित नए क्षेत्र मुनिवित्त करने में सहायता मिलेगी। अनीपचारिक बातावरण में विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया राष्ट्रमण्डल की भावना का निचोड़ है।

प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने कहा कि हम सच्चे धर्मों में एक दूसरे पर निर्भर रहने में विश्वास रखते हैं लेकिन जब तक सभी के हित समान नहीं होंगे इस प्रकार की गरस्पर निर्भरता का कोई अर्थ नहीं होगा। राष्ट्रों तथा लोगों के हितों की यह पारस्परिक समानता, जिसकी कि परस्पर निर्भर रहने वाले विश्व में माँग है, का लक्ष्य सभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि न्याय और समानता पर आधारित एक नयी

विश्व-व्यवस्था की स्थापना करने में हम सफल न हो जाएँ। श्रीमती गांधी ने तेल-संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि तेल के संकट से विकसित तथा समृद्ध देश भी प्रभावित हुए हैं जो निरन्तर घटते जा रहे हैं। इस संसाधन के लिए बेकाफी बड़े भाग का उपयोग करते हैं। अधिक से अधिक तेल प्राप्त करने के उनके प्रयासों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह बहुत ही आवश्यक लग रहा है कि तेल-उत्पादक एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके एक ऐसी योजना बनाएँ जिससे सभी बड़े-छोटे उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार तेल की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि शान्ति, समझौते और विकास में हम सबकी ओर एक समान दिलचस्पी है उसी वजह से हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं परन्तु शान्ति की सम्भावनाओं में कमी आई है और हम सर्वश्रद्धास्थिरता की स्थिति देख रहे हैं। शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों में टकराव की वजह से हमारे पास-पस के देशों की स्थिरता और शान्तिपूर्ण विकास को खतरा उत्पन्न हो गया है। सामरिक महत्त्व के सधर्मों के दबाव से कोई राष्ट्र अछूता नहीं रह सकता है न ही वह युद्ध की लपट से बचा रह सकता है। अब सबसे अधिक शक्तिशाली देश भी स्वयं को असुरक्षित समझ रहे हैं। अफगानिस्तान संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संकट अक्षुण्ण बना हुआ है। हम किसी भी राष्ट्र के अन्दरूनी मामलों में किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं लेकिन ऐसी जटिल समस्याओं को जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, सुलभाने में तरफदारी का रुख या तात्कालिक सम्मेलन राजनीतिक बुद्धिमत्ता का स्थान नहीं ले सकते। दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह रणस्थली रही है और अभी भी वहाँ अशांति है। वहाँ फिर बड़ी शक्तियों के स्वार्थ की टकराव हो रही है।

ओटावा शिखर सम्मेलन (जुलाई 1981)

विश्व के सात विकसित राष्ट्रों के जुलाई 1981 के ओटावा शिखर सम्मेलन में अनेक प्रश्नों पर विचार-विमर्श के बावजूद पूर्व-पश्चिम व्यापार, गरीब व अमीर देशों के बीच संवाद तथा विश्व में नई अर्थव्यवस्था लाने के उपायों आदि जैसे प्रश्नों पर अधिक प्रगति नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि विकासशील देशों के साथ सहयोग और उन्हें सहायता देते रहने के प्रश्न पर विकसित देशों ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। आगामी मैक्सिको शिखर सम्मेलन में उत्तर-दक्षिण आर्थिक संवाद के बारे में श्रद्धायोग की सिफारिशों पर विचार-विनिमय के लिए सभी विकसित देश महमत हो गए।

परस्पर हित—विकासशील देशों के साथ सहयोग और उनकी सहायता को विकसित देशों ने परस्पर हित का प्रश्न माना। एक प्रकार से इस शिखर सम्मेलन द्वारा पश्चिमी देशों ने विकासशील देशों को आश्वासन ही दिया कि सद्भाव और महमति की भावना के साथ सहयोग और विकास में इनकी सहायता की जाएगी। सम्मेलन के बाद प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि सभी विकसित देश विश्व अर्थव्यवस्था पर नये दिरे से विचार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए

तैयार हैं। इस बातचीत से तीसरी दुनिया के देशों को विकास सहायता देने के पश्चिमी कार्यक्रमों में समन्वय रखा जा सकेगा। नई अर्थव्यवस्था पर अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता सम्बन्धी सम्मेलन के निर्णय को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया।

नई अर्थव्यवस्था पर अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता के बारे में अमेरिका को शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले ही कुछ आपत्ति थी, लेकिन ओटावा शिखर सम्मेलन ने अमेरिकी आपत्ति को अनदेखा करते हुए यही तय किया कि इस प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। निश्चय ही इसके अच्छे परिणाम निकलेगे। शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सहायता के बारे में भावी स्तर को लेकर रीगन प्रशासन ने कोई बचन नहीं दिया है।

विकासशील देशों के लिए ऊर्जा के नये स्रोतों के ढूँढ़ने के बारे में एक विश्व ऊर्जा बैंक बनाने के यूरोपीय मुद्दा का इस शिखर सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से कोई उल्लेख नहीं हुआ लेकिन सभी सात विकसित देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि इस प्रकार के उपाय ढूँढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं। तेल-उत्पादक देशों से शिखर सम्मेलन की ओर से अनुरोध किया गया कि ऊर्जा के क्षेत्र में वे विकासशील देशों की भरसक सहायता करें।

संयुक्त विज्ञप्ति—सम्मेलन के बाद प्रकाशित व्यापक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि "भाज की परस्पर निर्भरता की दुनिया में विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं और अपनी नीतियाँ निर्धारित करते समय विकसित देशों को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। हम सहयोग की भावना से इन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने का अपना निश्चय व्यक्त करते हैं। अपने देश के लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करने और विश्व में आर्थिक समृद्धि बढ़ाने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए विकसित देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने होंगे।" विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत से परिवर्तन लाने की आवश्यकता अनुभव करने के साथ-साथ शिखर सम्मेलन में मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण पाने की आवश्यकता पर सबसे अधिक जोर दिया गया।

संयुक्त विज्ञप्ति की एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि विकासशील देशों की स्थिरता और स्वतन्त्रता तथा गुट-निरपेक्ष नीति का सभी विकसित देशों ने समर्थन किया और इन सभी देशों की प्रभुसत्ता तथा स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए इनके साथ पूर्ण सहयोग का बचन दिया। यह बात भी विकसित देशों ने स्वीकार की कि विश्व अर्थव्यवस्था ने विकासशील देशों की महत्वपूर्ण भूमिका और सहयोग उनके अपने हित में है। साथ ही विकसित देशों ने सोवियत संघ से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वह विकास सहायता के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए, और विकासशील देशों के निर्माण में पहले से अधिक भाग ले, लेकिन साथ ही इन देशों की प्रभुसत्ता और गुटनिरपेक्षता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

ओटावा सम्मेलन ने विकासशील देशों में अन्न की उपज बढ़ाने की आवश्यकता को सर्वाधिक महत्व दिया। सम्मेलन का विचार था कि इन देशों में अनाज और

कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य कम होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर सम्मेलन ने अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की। उनका विचार था कि यद्यपि विकासशील देशों में जनसंख्या पर नियन्त्रण पाने के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयत्न किए जाने चाहिए। व्यापार में उदार नीति अपनाने और 'गेट्टू' समझौते के अनुसार व्यापार प्रणाली को विकसित करने की बात समुक्त विज्ञप्ति में साफ तौर से कही गई।

उत्तर-दक्षिण संवाद के प्रश्न पर अमेरिका की पराजय—ग्रोटावा शिलर सम्मेलन शुरू होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति रीनाल्ड रीगन ने विकसित देशों के शासनाध्यक्षों से अनुरोध किया था कि प्रस्तावित सम्मेलन में तीसरी दुनिया के देशों की सहायता देने अथवा उनसे सहयोग के प्रश्नों पर उतना नहीं जितना कि विकसित देशों के द्वि-पक्षीय मामलों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन ग्रोटावा शिलर सम्मेलन के शुरू होते ही अमेरिका के इस अनुरोध की अवहेलना स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। मात राष्ट्रो के इस शिलर सम्मेलन ने समुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पहले ही विकासशील देशों के प्रश्न पर कुछ ऐसे निर्णय ले लिए थे जिन्हें अन्ततः अमेरिका को मानना ही पड़ा। नई विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता को लेकर एक प्रकार से इस सम्मेलन में अमेरिका की पराजय ही हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा मिटेरा, पश्चिम जर्मनी के चांसलर हेल्मुट श्मिड और कनाडा के प्रधानमन्त्री पियरे ट्रूदो ने अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता में पश्चिमी देशों के भाग लेने की जोरदार हिमायत की। जापान, इटली और ब्रिटेन के प्रधानमन्त्रियों ने भी यही विचार व्यक्त किया।

सोवियत सघ के साथ इस सम्बन्ध में वार्ता को लेकर प्रायः सभी विकसित देशों की राय थी कि शक्ति के आधार पर ही सोवियत सघ से बात हो सकती है। कनाडा के प्रधानमन्त्री पियरे ट्रूदो ने तो यहाँ तक कह दिया कि सामरिक दृष्टि से सोवियत सघ को धेड़टना प्राप्त करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, पर इन बात पर सभी सहमत थे कि निश्चीकरण तथा विश्व शान्ति आज के विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पश्चिमेशिया के बारे में विकसित देश चिन्ता व्यक्त करके ही रह गए। इजरायल और अरब देशों में सयम से काम लेने का अनुरोध जरूर किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना तथा मुकाव सम्मेलन के सामने नहीं आए।

ग्रोटावा शिलर सम्मेलन की समुक्त विज्ञप्ति से आभास मिला कि उत्तर-दक्षिण संवाद और विकासशील देशों की सहायता आदि जैसे प्रश्नों पर भी विकसित देश सहमत थे लेकिन कच्चे माल और विकसित देशों के बाजारों में विकासशील देशों के तैयार माल की बिक्री के लिए अधिकाधिक सुविधाएँ देने तथा मुद्रा-मुधार आदि जैसे प्रश्नों पर विज्ञप्ति में कुछ नहीं कहा गया। कुल मिलाकर नई अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता और विकासशील देशों की सहायता, इस सम्मेलन की

प्रगति कही जा सकती है परन्तु विकसित देशों ने अपनी समस्याओं को लेकर सम्मेलन में जितना विचार-विमर्श किया है उतना विकासशील देशों की तत्कालिक समस्याओं का विचार नहीं किया गया, फिर भी ओटावा सम्मेलन नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम कहा सकता है।

आंटिगुआ : 349 साल बाद स्वाधीन

31 अक्तूबर, 1981 को प्राची रात के बाद ब्रिटेन ने अपने एक ग़ौर उपनिवेश आंटिगुआ को स्वाधीनता प्रदान कर दी। 349 साल तक ब्रितानी शासन में रहने के बाद इस द्वीप को आजादी के दस्तावेज़ राजकुमारी मारग्रेट के हाथों से प्राप्त हुए। कॅरोबियाई सागर में स्थित आंटिगुआ के प्लावा बरबुदा और रिडोडा द्वीप इस नवस्वाधीन देश के भाग हैं।

प्रधानमन्त्री बर्ड ने क्रिकेट मैदान में जुड़े लोगों से स्वाधीनता दिवस पर दिए गये अपने भाषण में जहाँ ब्रिटेन से पुष्ता मंत्री की प्रतिबद्धता व्यक्त की वहाँ अपने देश के युवाओं से अनुशासन और बड़े परिश्रम से आंटिगुआ को नई शक्ति देने का आग्रह किया। बेशक आंटिगुआ के ब्रिटेन से औपचारिक सम्बन्ध समाप्त हो गए लेकिन उनसे एक नए तरह का रिश्ता कामम हुआ है—परस्पर मंत्री और समानता का।

यद्यपि अभी तक तीनों द्वीपों में एकता है लेकिन बड़े द्वीप बरबुदा में पृथक्तावादी तरव सक्रिय हैं, जहाँ की जनसंख्या मात्र डेढ़ हजार है। 1974 से लेकर अभी तक जो छोटे-छोटे द्वीप स्वाधीन हुए हैं वे हैं ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, होमानिका और सेंट विसेंट। इन सभी द्वीपों की आजादी सवा लाख से कुछ कम ही होगी। देखना यह है कि प्रधानमन्त्री बर्ड किस प्रकार अपने देश के भीतर के पृथक्तावादी तत्त्वों और पड़ोसियों में तालमेल बिठाने में सफल होते हैं।

राष्ट्रकुल सम्मेलन, सितम्बर-अक्तूबर 1981

मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) में 45 में से 41 राष्ट्रकुल देशों के राज्याध्यक्षों और जगसनाध्यक्षों का आठ दिवसीय (30 सितम्बर से 7 अक्तूबर 1981) शिखर सम्मेलन कई मायने में महत्वपूर्ण और उपयोगी रहा। जहाँ एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, यूरोप के कई छोटे-बड़े देशों के नेता जुड़े हो, उनमें मतभेद होना कोई अनहोनी बात नहीं। अलबत्ता किन्हीं मुद्दों पर सहमति को बेशक उपलब्धि माना जाएगा। मोटे तौर पर आर्थिक और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के मुद्दों पर सभी देशों में लगभग सहमति थी, औद्योगिकृत उत्तर और अविकसित दक्षिण के देशों में निरन्तर बढ़ती हुई खाई पर भी चर्चा हुई। उत्तर-दक्षिण संवाद द्वारा दूरी कम करने के प्रयास सफल नहीं हुए। गुटनिरपेक्ष देशों का अगला शिखर सम्मेलन (1983) नई दिल्ली में आयोजित होने के फँसले के बाद मेलबोर्न सम्मेलन सद्भावपूर्ण वातावरण में समाप्त हो गया।

सम्मेलन में दो बड़े देशों—अमेरिका और सोवियत सघ में बढ़ती हुई स्पर्धा से विश्व और मानव-जाति को सम्भावित संकट की ओर धकेलने की प्रवृत्ति को

घोर भी ध्यान दिलाया गया। 30 सितम्बर को अपने उद्घाटन भाषण में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माल्वम फ्रेजर ने कहा कि राष्ट्रकुल सम्मेलन कुछ ही दिनों बाद होने वाले उत्तर-दक्षिण मवाद के लिए सोचने के विभिन्न मुद्दे छोड़ जाएगा। उन्होंने नामीबिया के बारे में दक्षिण-अफ्रीका के रवैंये की भी आलोचना की। ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर ने आर्थिक मुद्दों के लिए व्यावहारिक और रचनात्मक रवैंया अपनाने का आग्रह किया। उनके अनुसार इस समस्या का समाधान वर्तमान धन का पुनर्वितरण नहीं है, बल्कि नये धन की प्राप्ति के लिए स्थितियाँ और स्रोत तैयार करना है। प्रधानमंत्री फ्रेजर ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी याद की जो राष्ट्रकुल के संस्थापक सदस्यों में से थे और जिन्होंने अपने जीते जी सभी सम्मेलनों में भाग लिया। जिवाब्वे के प्रधानमंत्री गवर्नर मुगाबे ने राष्ट्रकुल द्वारा उनके देश को स्वाधीनता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए दक्षिण-अफ्रीका के प्रति अमेरिका की मंत्री की नीति का विरोध किया। उनके अनुसार इससे नामीबिया की स्वाधीनता में विलम्ब ही होगा।

पहले दिन के भाषणों में पाँच प्रमुख वक्ताओं में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी भी थी। जिस प्रकार स्वर्गीय पण्डित नेहरू विश्व-राजनीति का व्यापक सर्वेक्षण करते थे वैसे ही भूमिका श्रीमती गाँधी ने मेलबोर्न सम्मेलन में निभायी। श्रीमती गाँधी ने शुरूआत अपने देश से की। पाकिस्तान का नाम लिये बिना कहा कि आज सुरक्षा और मंत्री के स्थान पर अनिश्चित आधुनिक सैनिक साज-सामान खरीदा जा रहा है। धीरे-धीरे शीतयुद्ध के खतरे का विस्तार होता जा रहा है जो हमारे द्वार पर दस्तक देता दीखता है। हमने द्वि-पक्षीय वार्ताओं द्वारा शान्तिपूर्ण स्थितियाँ स्थापित करने का हमेशा प्रयास किया।

श्रीमती गाँधी ने कहा कि इस समय विश्व दो बड़े सक्कों के दौर में है। पहला और बड़ा खतरा दो बड़े देशों में मुठभेड़ की भावना है जिसके फलस्वरूप वे अपने अस्त्रों के भण्डारों—परमाणु और परम्परागत दोनों को बढ़ाने की दौड़ में लग गए हैं। दूसरा मुद्दा अधिसंख्य देशों में आर्थिक क्षेत्र में निराशा की भावना है। इनसे मानव-जाति घुटन का अनुभव करती है और विरसित और विकासशील देशों में तार्दी निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों को दृष्टिकोण में रखते हुए राष्ट्रकुल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लिहाजा सदस्य देशों ने बड़ी शक्तियों से सचिन और सन्तुलित रवैंया अपनाने के लिए अपने-अपने प्रभावों के इस्तेमाल का आग्रह किया। आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री का विचार था कि सम्पन्न देश मरक्षणवादी नीतियाँ अपना रहे हैं। एक ओर तो आयातित मशीनों और औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं जिससे विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति दोराहे पर सड़ी है। दिलचस्प बात तो यह है कि बड़े देश अपनी मशीनों तो विकासशील देशों को बेच देते हैं, लेकिन उन मशीनों से बने माल का आयात नहीं करते। बेशक तेल की मूल्यवृद्धि का प्रभाव बड़े औद्योगिक देशों पर भी पड़ा है लेकिन अपने निरन्तर

बढ़ते निर्यात से उस पर वे पार पा ले जाते हैं जबकि गैर तेल उत्पादक देशों पर चारों ओर से दबाव पड़ता है और बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रकुल की यह धावाज कानकुन में उत्तर-दक्षिण सवाद के कानों तक पहुँचिगी। आर्थिक स्थिति के बारे में अलबत्ता राष्ट्रकुल के महासचिव श्रीदत्त रामफल ने 16 सूची कार्यक्रम प्रसारित किया।

कम्पूचिया और अफगानिस्तान के मुद्दों पर हुई बहस में श्रीमती गांधी ने कहा कि भारत चाहता है कि सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान से हटें लेकिन यह सम्बन्धित पक्षों में राजनैतिक वार्ता द्वारा ही सम्भव है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम्पूचिया में हेड सामरिन की सरकार को मान्यता सभी पक्षों का जायजा लेने के बाद दी है। प्रधानमन्त्री के नापण के बाद जाम्बिया के राष्ट्रपति केनेथ कोण्डा ने कहा—‘इन्दिरा जी लुसाका सम्मेलन में हमें आप का अभाव खला था।’ प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी का केनबरा में प्रेस क्लब का दो घण्टे का सवाददाता सम्मेलन वास्तव में चर्चा का विषय था। सभी मुद्दों पर बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिए गए। जैसे पाकिस्तान को राष्ट्रकुल में शामिल किए जाने के भारत के विरोध के उत्तर में कहा कि वह अब राष्ट्रकुल में नये शामिल होना चाहता है जबकि 1972 में उसने दसवीं सदस्यता छोड़ी थी तब तो वहाँ लोकतन्त्री मरफार थी।

अन्तिम दिन की वार्ता के बाद जारी होने वाली संयुक्त विज्ञप्ति के प्रारूप में 41 देशों के शासनाध्यक्षों ने सोवियत संघ और अमेरिका दोनों से हिन्द महासागर से सैनिक साज-सामान हटाने की माँग की ताकि तनाव समाप्त हो सके। अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों और कम्पूचिया से वियतनामी सैनिकों को हटाये जाने की माँग भी की गई। यद्यपि संयुक्त विज्ञप्ति के प्रारूप में दक्षिण-अफ्रीका का जिक्र नहीं है लेकिन आशा व्यक्त की गई कि 1982 के मध्य तक यह नामीबिया को स्वाधीनता प्रदान कर देगा। प्रारूप में पश्चिमेजिया, अफगानिस्तान और दक्षिण-पूर्वेशिया के मसलों पर कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। प्रारूप में वेनेजुएला और गुयाना में सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलभाने पर भी बल दिया गया और वेनेजुएला द्वारा, गुयाना के दो तिहाई भाग के दावे पर क्षोभ व्यक्त किया गया है। यद्यपि श्रीमती गांधी और अफ्रीकी देश राष्ट्रकुल सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करने और विश्व के राजनीतिज्ञों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे, लेकिन न्यूजीलैण्ड के प्रधानमन्त्री रॉबर्ट मल्डून, त्रिनामी प्रधानमन्त्री श्रीमती थेंचर आदि इस सम्मेलन से अधिक प्रसन्न नहीं दिखे। कनाडा के प्रधानमन्त्री पियरे त्रूडो ने अलबत्ता अफ्रीका के देशों के साथ नामीबिया की स्वाधीनता के प्रयास और ‘स्वाधी’ की सत्ता नोपने की माँग का समर्थन किया लेकिन थेंचर जो शुरू में इस मुद्दे पर उदासीन रही, बाद में सदस्य देशों की खासतौर पर अफ्रीकी देशों को, अपनी प्रभावी भूमिका का आश्वासन दिलाया।¹

मेलबोर्न सम्मेलन में भारत का वर्चस्व

मेलबोर्न के राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन का मूल्यांकन भारत के सन्दर्भ में भी करना होगा, क्योंकि यह सम्मेलन एक दृष्टि से भारत की सफलता का सम्मेलन था। विपक्ष परिस्थितियों और प्रबल विरोधी शक्तियों के बावजूद श्रीमती गांधी ने सम्मेलन में भारत की आवाज को ऊँचा उठाया और भारतीय नेतृत्व तथा नीतियों को छाप छोड़ा। भारत के सन्दर्भ में इस सम्मेलन का सही मूल्यांकन हमें 'शरदेन्दु' के इन शब्दों में मिलता है।¹

मेलबोर्न में सम्पन्न राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन भारत की नीतियों, विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के व्यक्तित्व तथा उनकी नीतियों की सफलता के लिए स्मरण किया जाएगा। अफगानिस्तान, कम्बूजिया, हिन्द महासागर जैसे विवादग्रस्त प्रश्नों पर भारत के दृष्टिकोण को व्यापक समर्थन मिला। तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमण्डल कोष को फिर से सक्रिय करने और मंजूरियों में निवृत्त भविष्य में हो रहे उत्तर-दक्षिण 'बानकुल' सम्मेलन में विकसशील देशों की ओर से एक साहसिक रख अपनाते तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विकसित विकासशील सवाद को बहुअपेक्षित राजनीतिक गति प्रदान करने का भी निश्चय किया गया। यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित 41 देशों का जो विश्व की एक चौथाई जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर उनकी आवाज का प्रभाव पड़ना निश्चिन है।

सम्मेलन की विजय—अफगानिस्तान और कम्बूजिया, इन दोनों प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विवादों पर विदेशी सेनाओं के हटाए जाने के साथ उनके राजनीतिक हल पर जोर दिया गया। भारत की निरन्तर यही नीति रही है कि श्रीमती थैंकर की तथा उनके कुछ समर्थकों की, इस बात को किसी ने गम्भीरता से नहीं लिया कि अफगानिस्तान में मोबियत मध्य से बिना जन सेनाओं हटाने को कहा जाए। साथ ही अफगानिस्तान के अन्दर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र की स्थिति और उसके पलितार्थ पर गहरी चिन्ता प्रकट कर राज्याध्यक्षों ने भारत की चिन्ता और आग्रह को ही अभिव्यक्ति दी। भारत बराबर यह कहता रहा है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दिए जाने से नए तनाव पैदा होंगे और शान्ति-सुरक्षा को खतरा बड़ेगा।

हिन्द महासागर के प्रश्न पर सम्मेलन ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि तटवर्ती तथा पृष्ठराज्यों की इच्छाओं के विपरीत उसमें बाहरी शक्तियों की मंजूर गतिविधियाँ बढ़ी हैं और शान्ति-सुरक्षा की स्थिति में बिगाड़ डूषा है। दिसम्बर 1971 के संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा-पत्र में हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र मानने की आग्रह को आघात पहुँचा है। सम्बद्ध राज्यों के क्षेत्र में दनाव के खत दूर करने के उपाय खोजने में सहयोग की माँग भी की गई है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेलबोर्न सम्मेलन भारत की सफलता का

सम्मेलन रहा, लेकिन इन राफतता को सही-सही और पूरे परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा।

लुसाका सम्मेलन—मेलबोर्न सम्मेलन से पहले राष्ट्रमण्डल लुसाका (जम्बिया) में हुआ था। उस समय हमारे देश में जनता पार्टी की सरकार पदावृत्त थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पाँच अपने देश की धरती पर बहुत कम टिक पाते थे और वह अपनी पार्टी की तथा भारत की विदेश-नीति समझाने के लिए विभिन्न राजधानियों के चक्कर लगाते रहते थे।

यह एक दुःखद सत्य है कि हमारे विदेश मन्त्री के कठोर परिश्रम के बाद भी लुसाका सम्मेलन में और उसके बाद हवाना में हुए निर्गुट सम्मेलन में, हमारे प्रतिनिधियों की आवाज बहुत दबी-दबी सी रही। इस सम्बन्ध में मेलबोर्न में जम्बिया के राष्ट्रपति कैनेथ कोण्डा के इन्दिराजी से कहे गये ये शब्द दिलचस्प थे : “हमें लुसाका में आपकी बहुत याद आई।”

ऐसी बात नहीं कि हमारी विदेशनीति में कोई मौलिक परिवर्तन आ गया था। जनता सरकार भी मेहरू जी की निर्गुट विदेश नीति पर ही चलने का दावा करती थी। वास्तविकता यह है कि आपसी भगडों के कारण जनता पार्टी को विदेश नीति की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला था। मिला होता, तो हमारा ख्याल है, हमारे देश की विदेश नीति भी वैसे ही बदल गई होती जैसे नागिर के बाद मिस्र की बदल गई। शासन से हटने के बाद तत्कालीन विदेशमन्त्री और तत्कालीन जनता पार्टी के प्रमुख नेता आज जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, उससे हमारे इस ख्याल को बल मिलता है।

भूतपूर्व इजरायली विदेशमन्त्री मोशे दायान ने अपनी एक पुस्तक में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के साथ अपनी एक गुप्त बैठक का उल्लेख किया है। वह काफी आशाओं के साथ दिल्ली आए थे, लेकिन यदि मोरारजी उनसे सहानुभूति रखते हुए भी उनकी आशाओं को पूरा नहीं कर सके तो इसीलिए कि जनता में उसकी तीव्र प्रतिक्रिया होने का भय था। हाँ, यदि जनता पार्टी को कुछ अधिक समय शासन का अवसर मिल जाता, तो परिवर्तन सम्भव था।

अतः पहली बात तो यह है कि लुसाका सम्मेलन की पृष्ठभूमि में हमें मेलबोर्न सम्मेलन में इन्दिराजी की सकलता को याद करना चाहिए।

रीगन प्रशासन का रुख—दूसरी बात वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की है। अमेरिका में जब से रीगन प्रशासन आया है, वह निरन्तर हमको नीचा दिखाने, हमारी कठिनाइयाँ बढ़ाने, हमारी सीमा पर हथियारबन्दी करने और हमको अपने मित्रों से काटने के प्रयत्न कर रहा है। यह एक दुःखद स्थिति है। भारत और अमेरिका विश्व के दो सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश हैं और उनका हित मध्योय में है, टकराव में नहीं। लोकतन्त्र के भविष्य के हित में भी यही है कि लेकिन अभी अमेरिकी नीतियों में परिवर्तन का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अन्नबर सादात की हत्या के बाद आए तो वह नहीं सजते।

अफगानिस्तान और कम्बूजिया, ये दो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विवाद ऐसे हैं जिनकी छाड़ में हमको काटने के ये प्रयत्न जारी हैं। इन्दिराजी ने राष्ट्रमण्डल

सम्मेलन में जिस प्रकार अपना दृष्टिकोण उपस्थित किया, उससे हमारे आलोचकों को भी हमारे पक्ष को स्वीकार करना पड़ा।

यही कारण है कि राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भारत और इन्दिराजी की एक नयी छवि उभरकर सामने आई। निर्गुट, विकामजील और अधिकसित देशों को पुनः यह विश्वास होने लगा कि नासिर-नेहरू-टीटो त्रिगुट के रगमच से विदा हो जाने के बाद अब इन्दिराजी ही उनको सबल नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं। लुसाका और हवाना में हमने जो प्रतिष्ठा खोई थी, वह मेलबोर्न में पुनः प्राप्त कर ली, यत्कि उमें पहले से अधिक बढ़ा लिया।

इस सम्बन्ध में हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि मेलबोर्न में इन्दिराजी की टक्कर एक अन्य महिला प्रधानमन्त्री मार्ग्रेट थैचर से थी। एक तो ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री होने के नाते, जिसे राष्ट्रमण्डल का नया समझा जाता रहा है, दूसरे स्वयं लौह-महिला के रूप में विख्यात होने के कारण थैचर की इन्दिराजी से यह टक्कर अत्यन्त दिलचस्प थी।

मेलबोर्न और कॅनबरा में हुआ इन्दिराजी का भव्य स्वागत, उनका सवाददाता सम्मेलन, अन्तिम विज्ञप्ति में भारतीय दृष्टिकोण का ऊपर रहना, इन सब बातों से किसी को सन्देह नहीं रह जाना चाहिए कि दो लौह-महिलाओं की टक्कर में विजय जिसकी रही। पहली बार यह महसूस हुआ कि राष्ट्रमण्डल का नेतृत्व ब्रिटेन के हाथों से निकल गया है। श्रीमती थैचर ने भी ज़रूर बंसा ही अनुभव किया होगा जैसा ऊँट पहाड़ के नीचे आने पर करता है। इसके लिए श्रीमती थैचर की वह नीति ही जिम्मेदार है जिसके अन्तर्गत वह हर प्रश्न पर राष्ट्रपति रीगन की नीतियों के अनुकरण का प्रयत्न कर रही है।

मेलबोर्न सम्मेलन के बाद अब हमें 1983 में नयी दिल्ली में अगले राष्ट्रमण्डल सम्मेलन की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

कॅनकुन शिखर सम्मेलन (अक्टूबर 1981)

कैरेबियन सागर के तटवर्ती द्वीप पर बसे कॅनकुन शहर में 22-23 अक्टूबर 1981 को निम्नलिखित 22 देशों का एक शिखर सम्मेलन तीसरी दुनिया के आर्थिक मन्दत के सन्दर्भ में हुआ—

1. संयुक्त राज्य अमेरिका, 2. कनाडा, 3. ब्रिटेन, 4. फ्रांस, 5. पश्चिमी जर्मनी, 6. स्वीडन, 7. आस्ट्रिया, 8. जापान, 9. यूगोस्लाविया, 10. चीन, 11. भारत, 12. मऊदी अरब, 13. नाइजीरिया, 14. तन्जानिया, 15. अल्जीरिया, 16. बंगला देश, 17. फिलिपाइन्स, 18. मैक्सिको, 19. वेनेजुएला, 20. गुयाना, 21. आईवरीकोस्ट, तथा 22. ब्राजील।

सूची से स्पष्ट है कि 14 चुनिंदा देशों के प्रतिनिधि, 8 अमीर देशों के मरॉच्च नेताओं से विचार विमर्श के लिए कॅनकुन में आए। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ऐसे ही इस क्षण पर कि बातचीत के नये कोई पूर्व निर्धारित कार्य-सूची नहीं होगी और

दो दिन के शिखर मिलान के बाद संयुक्त विज्ञप्ति भी प्रकाशित नहीं की जायेगी। इसके कई कारण थे। एक तो यही कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सम्मिलित बैठक में वह अपना खैया प्रकट कर चुके थे। दूसरे, तीसरी दुनिया के अधिक मरुट के बारे में प्रपेक्षनया उदार दृष्टिकोण वाले फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन में उनका मतवैभिन्न्य, औपचारिक रूप से प्रकट न हो। तीसरे, अमेरिकी शासक संयुक्तराष्ट्र आदि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुभव से खुश नहीं है—उन्हें पसंद नहीं कि तीसरी दुनिया के देश उनकी कारमुजारियों पर टीका-टिप्पणियाँ करें। यदि इस सम्मेलन की कार्यवाही औपचारिक ढंग से होनी तो दोनों विरोधी राष्ट्रपति गीगन को यह श्रेय न मिलना कि उन्होंने संयुक्तराष्ट्र संगठन में इन विषयों पर आगे बात चलाने की सहमति दे दी है।

क्योंकि कैनकुन में गिनेचुने 22 देशों के शासकों को आमने सामने बातचीत करने का, मिलने जुलने का, इसलिए एक दूसरे के दृष्टिकोण को व्यक्तिगत स्तर पर समझने का मौका मिला। इसलिए 'सीहार्न और परस्पर विश्वास' की औपचारिक अभिव्यक्ति को भी एक अनिश्चित उपलब्धि माना गया। लेकिन इसकी जाँच बहुत जल्द हो जायेगी जब संयुक्तराष्ट्र महासभा में जल्द ही ये मामले उठाये जायेंगे।

शिखर सम्मेलनों में पहले से तय विषयों और परस्पर सहमति के मुद्दों को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या फिर एक दूसरे का हल समझने के लिए और मोदेबाजी के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कैनकुन सम्मेलन को शिष्टाचार से 'एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' की दिशा में एक कदम की सजा दी गई है पर अधिक से अधिक वह अनमने ढंग से दूसरे उद्देश्य की पूर्ति ही करता दिखाई दिया।

कैनकुन शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों के निर्यात से जुड़ी समस्याओं के सन्दर्भ में भारत की ओर से एक पाँचसूत्री योजना प्रस्तुत की गई। यह सम्मेलन के दस्तावेजों में सम्मिलित तो कर ली गई, लेकिन विकासशील देशों के 'दृष्टिकोण' से ऊपर का दर्जा नहीं पा सकी। यो इसके सभी सूत्र समय-समय पर अन्य मन्त्रों पर और बैठकों में भी उल्टे रहे हैं। पाँच सूत्र निम्नलिखित हैं—

- (1) जिसों के आयात-निर्यात के बारे में नये सिरे से समझौते किये जाएँ।
- (2) जिसों के भाव स्थिर करने के लिए अकटाड (संयुक्तराष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन) के तत्वावधान में साम्ना कोष बनाने की प्रक्रिया को तुरन्त गतिशील बनाया जाये।
- (3) बरीयता देने की सामान्य योजना को व्यापक बनाया जाये और विकासशील देशों में निर्यात वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रवृत्ति को रोका और घटाया जाये।
- (4) देशों (जुड कपास आदि) सम्बन्धी समझौते के नवीनीकरण के लिए बातचीत जल्द शुरू की जाये।
- (5) विकासशील देशों के निर्यात पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों की समीक्षा का बन्दोबस्त हो और उन्हें एक निर्धारित अवधि में क्रमशः समाप्त किया जाये।

इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता बतारते हुए भारतीय दस्तावेज में कहा गया “ऐसा लगता है कि निर्यात वृद्धि की दर में कमी के साथ निर्यात में उपलब्धि भी घटेगी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से उधार ली गई पूँजी की लागत (व्याज दर) भी अधिक होगी और सरकारी स्तर पर मिलने वाली सहायता की संभावनाएँ भी कम होती जा रही हैं।”

विषम अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विषमता घटाने में दुनिया के सम्पन्न देशों की दिलचस्पी नहीं है। इन देशों में दुनिया की एक चौथाई आवादी रहती है लेकिन आमदनी में उनकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है। इसके बावजूद अगर वे महँगाई, बेरोजगारी और विकास दर में ह्रास का सामना कर रहे हैं तो इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। उनके उत्तरोत्तर अधिक पूँजी बहुल उद्योग देशवासियों को पूर्ण रोजगार नहीं दे सकते। हथियारों या ऐसी ही अन्य स्फीतिकारी मदों पर व्यय महँगाई को जन्म देता है। वे इन असन्तुलनों को ढो पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वे उद्योग, व्यापार और प्रौद्योगिकी के जरिए विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए मौजूदा स्थिति बनाए रखने में ही उनका निहित स्वार्थ है। वे नहीं चाहते कि विकासशील देशों की अर्थ-रचनाएँ उनके चंगुल से मुक्त होने के प्रयास में सफल हो सकें, पश्चिम के कुछ देशों का दृष्टिकोण अगर अपेक्षा उदार दीखता है तो इसलिए भी कि अन्तर्राष्ट्रीय शोषणतन्त्र में उनकी हिस्सेदारी कम है और अमेरिका का आर्थिक, सामरिक वर्चस्व उनके लिए कष्टकर है।

यही वजह है कि अमेरिका के नेतृत्व में विकसित देश कृषि या खनन में उपलब्ध जितने के वास्तविक मूल्य सुरक्षित रखने की कोई बातचीत बनाने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसी जितने के निर्यातक विकासशील देश हैं। इन जितने के निर्यात मूल्य के कारण विकासशील देशों की आमदनी कहीं इतनी घट जाती है कि वे तबाही के कगार पर पहुँच जाते हैं।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और उनकी सस्यामों से अपेक्षा कम व्याज पर मिलने वाले ऋणों की राशि बढ़ाने का अमेरिका बहुत विरोध कर रहा है। उसकी मशा है कि ऐसी ‘सहायता’ कम कर के विकासशील देशों को मजबूर किया जाए कि वे पश्चिमी देशों के बैंकों से ऊँची दर पर अल्पकालिक ऋण लें अथवा बहुराष्ट्रीय निगमों पर निर्भर हो जायें—इससे न केवल पश्चिमी पूँजी पर मुनाफा बढ़ेगा वरन् विकासशील देशों की अर्थरचना पर पश्चिम के प्रौद्योगिक और व्यापारिक तन्त्र की पकड़ बढ़ेगी।

इसमें यह समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि अमेरिका विश्व-बैंक मुद्राकोष के सविधान को लोकतन्त्री बनाने का क्यों विरोध कर रहा है। उसका अध्यय हमेशा अमेरिकी होता है और पश्चिमी देशों की सहमति के बिना ये समस्याएँ कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकती। मंकनमारा के कार्यकाल में तीन आयातक देशों की सहायता के लिए एक ऊर्जा कोष बनाने का फैसला किया गया था, मगर

अब वह खटाई में पड़ गया है। इस सम्मेलन में केवल यह मनवाया जा सका है कि ऐसे देशों की सहायता के लिए कुछ अतिरिक्त राशि मुहैया की जाएगी।

विश्व बैंक और मुद्रा कोष को अन्तर्राष्ट्रीय जरूरतों के मुताबिक सक्रिय करने के प्रस्ताव भी विभिन्न देशों ने अनदेखे कर दिए क्योंकि ये न तो अपने अधिकारों में कमी के लिए तैयार हैं और न विशेष ऋणपत्र (एस. डी. धार.) योजना को आगे बढ़ाने या मुद्राकोष में हिस्सेदारी की व्यवस्था में बदलाव के लिए ही।

खनिज तेल के भावों में वृद्धि के कारण विकासशील देशों की कठिनाइयाँ कई गुना बढ़ गयी हैं। विकसित देश तो लागत मूल्य में वृद्धि के मुताबिक अपने निर्यात का भाव बढ़ा लेते हैं, लेकिन अन्य तेल आयातक विकासशील देशों पर दोहरी मार पड़ रही है। उनके आयात महँगे हुए तो हुए, तेज निर्यात की कमाई का वह हिस्सा जो उन्हें मिल सकता था वह भी पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा किया जा रहा है। यानी तेज के घनी अरब देशों का धन या तो सहचर देशों का या पश्चिमी अर्थ-रचनाओं को मजबूत बना रहा है।

कैनकुन सम्मेलन में सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब के राजकुमार फहद और सबसे बड़े तेलिन भिन्न प्रकार के विकासशील देश चीन के प्रधानमंत्री भी सम्मेलन में पधारे थे। इन दोनों ने मुख्यतः प्रेक्षक की भूमिका निभाई। सऊदी अरब तेल के भाव बढ़ाने के मामले में अन्य विकासशील देशों का समर्थन ले तो लेता है, मगर तेल से अर्जित डॉलरों के निवेश के मामले में पश्चिमोन्मुखी है। चीन ने 1957 से अभी तक तथाकथित विदेशी सहायता के बिना अपना आर्थिक विकास किया है। अब वह पश्चिमी दुनिया से अपनी शर्तों पर ऋण और सहायता प्राप्त कर सकेगा। यदि भारत जैसे अन्य अनेक देश भी पश्चिमी ढर्रे पर चलते तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती थी और उसी हद तक विकासशील देशों की सौदेबाजी की शक्ति भी।

कैनकुन के खतरे

कैनकुन के 22 राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में ग्रामतौर से लोगों को इतना ही देखने योग्य दिखा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय था और हमारे देश की प्रधान मंत्री बड़े बड़े विश्व नेताओं से मिली चीन के प्रधानमंत्री से भी और अमेरिका के राष्ट्रपति से भी। दोनों इस समय एशिया पर जाना चाहते हैं मगर दोनों ने हमारी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया और उसको देखकर मुस्कराये और इस दृश्य की फोटो भी छपी। यह बहुत कम लोग सोच रहे होंगे कि इस विश्व शिखर सम्मेलन का हमारे राष्ट्र की अपनी व्यवस्था और अर्थन से क्या सम्बन्ध है। परती के औद्योगिक कच्चे माल और मानवीय श्रम पर अप्रत्यक्ष रूप से कच्चा ही इस वक्त दुनिया के बड़े औद्योगिक देशों का उद्देश्य है। लगभग 140 विकासशील देशों में दस पीछे एक ने ही इस सम्मेलन के आठ बड़े गुंथटालों के साथ मिल बैठकर विकास की नई चिन्ताओं पर बात करना स्वीकार किया। यह अपने आप में कुछ मायने रखता है : यही कि यह सिर्फ कुछ ऐसे समझौतों के उद्देश्य से हुआ था जिनमें खास खास लोगों की सहमति मिल सकी।

14 विकासशील देशों में भारत एक था। बाकी तीन धनी तेली देश आदि थे जो किसी न किसी रूप में बड़े औद्योगिक देशों की नकल करने की कोशिश में है। भारतीय राष्ट्र से संबंध रखने वाला प्रश्न यह है कि क्या हम भी विकसित शोषक देशों की नकल करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या विश्व के शोषण में तथा मानवता के खडन में लगे हुए बड़े राष्ट्रों की पड़्यत्र नीति में कहीं न कहीं शामिल हो रहे हैं या कि कुछ ऐसा चिंतन कर रहे हैं जिससे उस पड़्यत्र का कार्यशील विरोध हो सके। दूसरे शब्दों में, क्या हम एक भारतीय व्यक्तिगत खोज या बना रहे हैं जो कि विश्व मंच पर शोषित देशों की भी प्रतिछवि हो और भारतीय शोषित जनता की भी। श्रीमती गांधी ने सम्मेलन के बाद कहा—और विनम्रता में ही कहा होगा—कि भारत ने नेता बनने की कोशिश कभी नहीं की। हम मानते हैं कि विश्व की समस्याएँ इतनी बिराट हैं कि हर एक को मिल कर ही काम करना होगा। आशा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि विकासशील देशों के शोषणधर्म और क्रूर चिंतन के अनुसार अपने-अपने देशों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कैंकून के सम्मेलन में किसी भारतीय विचारधारा का टकराव रीगन की विश्वविजय की विचारधारा से नहीं हुआ है। दोनों ही कैंकून को कमो-बेश प्रगति का सूचक मान रहे हैं। रीगन कह रहे हैं कि गरीब देशों की सहायता के मामले में इस उत्तर-दक्षिण शिखर सम्मेलन में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। इन्दिरा गांधी कह रही हैं कि यह अच्छा लक्षण है कि भविष्य में ऐसे आर्थिक विषयों पर विश्व बहस का रास्ता बंद नहीं हो गया है। दोनों बातों में क्या अंतर है? क्या केवल यही कि रीगन कहते हैं कि विदेशी सहायता किन-किन कामों में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। उसी पहचान के वास्ते सम्मेलन में खुल कर बहस हुई और श्रीमती गांधी कह रही हैं कि विकास के लिए गरीब देशों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण विषय सम्मेलन की सारांश विज्ञप्ति में उल्लिखित नहीं हुआ। साथ में उनकी यह शिकायत भी जोड़ लें कि अन्तर्राष्ट्रीय सत्थाएँ भेद देने के बहाने अपनी विचारधाराएँ न लादने पायें तो दोनों नेताओं के विचारों का परस्पर सम्बन्ध खुल कर प्रकट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं पूरक ही हैं। जिन विचारधाराओं के बहाने इनमें प्रवेश कर जने से शका श्रीमती गांधी ने प्रकट की है वे विचारधाराएँ स्वयं हमारे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में हमारे ही निर्णयों के कारण प्रवेश कर चुकी हैं और अभी और करती जायेंगी। तब केवल दंतना ही करना बाकी रह जायेगा कि अगले सम्मेलन की सारांश सूची में वे सब आवश्यकताएँ बता दी जायें जिनको रीगन भारत या अन्य देशों के लिए ज्यादा बड़ी आवश्यकताएँ मानते हैं और किसी को यह कहने का मौका न मिले कि अमेरिकी या पश्चिमी शक्तों पर यह सहायता ली गई है क्योंकि तब तक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत से अर्थों में अमेरिकी शोषणवाद के बहुत नजदीक अपने प्राप पहुँच चुकी होगी।

कैंकून सम्मेलन ने दिया दिया है—बशर्ते कि देखने वाले विरमिन् देशों के साथ

बैठ कर अपने यहाँ की जनता पर रूप्राब डालने में मग्न न हो गये हों—कि यदि ऐसे ही सम्मेलन दो-चार बार और हुए और उनमें से किसी तरह की विचारधारा या अर्थव्यवस्था के अंतरों को उभारा नहीं गया तो विकासशील देशों के लिए अमेरिकी और पश्चिम के बाजार चक्र में फँस जाना ही उनकी नियति हो जाएगी—इस नियति से भाग कर वे किसी दूसरे क्षिविर में नहीं जा सकेंगे क्योंकि तब तक सभी क्षिविरो का उद्देश्य एक ही हो चुका होगा।

भारत-अमेरिका सम्बन्ध सुधार के प्रयास

रीमन प्रशासन का रख रखापि पूर्णतया भारत विरोधी है, तथापि 1981 के प्रारम्भ चरण से भारत और अमेरिका के बीच सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास शुरू हुआ है। इन प्रयासों के गतिशील बनाने तथा मतभेदों को यथाशक्ति दूर करने के उद्देश्य से अमेरिका के विदेश मंत्री अल्वेजोण्डर हेग की भारत यात्रा को एक शुभ संकेत माना जा सकता है। प्रख्यात समालोचक दिनेश कुमार मिश्र ने भारत-अमेरिका सम्बन्धों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करते हुए वर्तमान सम्बन्ध-सुधार के प्रयासों का जो जायजा लिया है वह मुक्तिमंगल और तथ्यपरक है।

हमारे देश के प्रति अभी तक अमेरिकी प्रशासन का जो रुख रहा है उससे यही प्रकट होता है कि अमेरिका ने एशिया, मुख्य रूप से दक्षिण एशिया की राजनीति को समझने तथा प्रभावित करने में भारतीय दृष्टिकोण को कोई गहत्व न देने का फैसला कर लिया है। किन्तु कान्फ्रुन (मैक्सिको) सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीमन से वार्ता के बाद अमेरिकी दृष्टिकोण में कुछ अन्तर दिखाई देता है। विदेशमंत्री अलेजोण्डर हेग की दिल्ली-यात्रा पर इसी सन्दर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

भारत तथा अन्य निगुंट राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के साथ किसी सैन्य सन्धि से बचे तो नहीं हैं, किन्तु दुनिया आज इतनी सिमट गई है तथा राजनीति का प्रभाव इतना व्यापक हो गया है कि कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता है कि आधुनिक विश्व के ज्वलन्त प्रश्नों के प्रति उसका दृष्टिकोण बिल्कुल तटस्थ है। जिन राष्ट्रों की निगुंट नीति में आस्था है वे भी तटस्थ नहीं रह सकते हैं। निगुंट और तटस्थ दो अलग-अलग शब्द हैं। पहला सुविचारित नीति को प्रकट करता है तो दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह आवश्यक नहीं कि निगुंट राष्ट्र सभी मामलों में तटस्थ ही रहें। पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता के सवाल की ही लें। निगुंट भारत इस प्रश्न पर तटस्थ रहकर चुप्पी साधकर बैठा नहीं रह सकता है। इसलिए दक्षिणी एशिया में अमेरिका की शस्त्रीकरण की नीति का निगुंट भारत ने खुलकर विरोध किया है। इस प्रश्न पर वह तटस्थ नहीं रह सकता है।

भारत तथा अमेरिका के बीच पिछले 34 वर्षों के सम्बन्धों पर दृष्टिपात करने से जो बात उभर कर सामने आती है वह यह है कि दोनों देशों की राजनीतिक प्रणाली में समानता के बावजूद प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर दोनों के

दृष्टिकोणों में सदा अन्तर रहा है। यह तो स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका विश्व के दो सबसे बड़े लोकतन्त्र हैं। दोनों खुले समाज में विश्वास करते हैं किन्तु अमेरिकी प्रशासन ने आज तक भारत की इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं पर खुले दिमाग से विचार नहीं किया है। अमेरिकी नीतिकारों के लिए कम्युनिस्ट खेमे का अग्रग्राह्य सदा चिन्ता का विषय रहा है किन्तु यह अस्वाभाविक नहीं लगता है। वे जो भी रणनीति तैयार करते हैं उसका लक्ष्य सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार रोकना ही होता है। जो राष्ट्र इस व्यापक रणनीति में मोहरे के रूप में फिट होते हैं उन्हें तो अमेरिका मित्र मानता है किन्तु बाकी राष्ट्रों के प्रति उसका रुख यदि शत्रुतापूर्ण नहीं रहता हो तो रूखा तथा उपेक्षापूर्ण तो रहता ही है। भारत की शुमार ऐसे ही राष्ट्रों में की जा सकती है।

हम मानते हैं कि भारत तथा अमेरिका के बीच सहयोग और मंत्री इन दोनों देशों के हित में तो होगी ही, इससे विश्व-शान्ति को सुदृढ़ बनाने तथा दुनिया को परमाणु युद्ध के विनाश से बचाने में भी मदद मिलेगी।

भारत और अमेरिका के बीच नीति सम्बन्धी मतभेदों की सूची बहुत लम्बी है। इनमें कम्युनिज्म, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों व अन्य आधुनिक शस्त्रास्त्रों की सप्लाई करने का अमेरिका का फंसला हाल की घटनाएँ हैं। दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव दूर करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हर प्रश्न पर दोनों के दृष्टिकोण एक समान हों। भारत जैसा विशाल 70 करोड़ की आबादी वाला देश किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बन सकता है। यह बात अमेरिका तथा रूस दोनों महाशक्तियों के साथ हमारे सम्बन्धों पर लागू होनी है। नीतिगत मतभेदों के बावजूद मंत्री और सहयोग का विकास किया जा सकता है।

किन्तु साथ ही यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब तक अमेरिका भारत पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान को अत्याधुनिक तथा घातक शस्त्रास्त्रों से लैस करने का परित्याग नहीं करेगा तब तक सम्बन्धों में तनाव दूर करने की दिशा में असली मायने में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। फरवरी 1954 में अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान के साथ पहला समझौता किया था। भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में इससे जो दरार पड़ी उसे अभी तक पाटा नहीं जा सका है। अमेरिका ने भारत की निर्गुट विदेशनीति से परेशान और नाराज हो कर ही पाकिस्तान तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ राष्ट्रों को सैन्य सहायता देने का फंसला दिया था। उससे न तो अमेरिका को कोई लाभ प्राप्त हुआ न ही भारत तथा इस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों को, यह तो पिछले 25 वर्षों के इतिहास से स्पष्ट है।

पाकिस्तान ने कभी भी लोकतन्त्र तथा धर्म-निरपेक्षता में ग्राह्य नहीं प्रकट की है फिर भी पाकिस्तान के फौजी तानाशाहों को अमेरिका से लगातार आर्थिक और फौजी मदद मिलती रही। अमेरिका के चाहे जो भी इरादे हों, पाकिस्तानी शासकों का एक मात्र लक्ष्य फौजी ताकत के मामले में भारत के बराबर आना ही था। वे सत्तार की ताकत से कश्मीर पर वज्रा करने का स्वप्न देख रहे थे।

अमेरिकी पेंटन टैंको तथा सेवर जेट विमानों के मद में चूर पाकिस्तान के फौजी शासकों ने 1965 में कश्मीर हथियाने के लिए पहले तो धुसपैठिये भेजे और फिर भारत पर नग्न आक्रमण कर दिया। भारत वर्षों से जो आशंका प्रकट करता रहा था वह सच साबित हुआ। अमेरिकी प्रशासन का यह आश्वासन भूटा सिद्ध हुआ कि उसने पाकिस्तान को जो शस्त्रास्त्र दिए हैं उनका भारत के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जाएगा।

इतिहास की पुनरावृत्ति होनी है। लोकतन्त्री राष्ट्रों का नेता अमेरिका पुनः पाकिस्तान के फौजी तानाशाह जनरल जिया-उल-हक को अत्याधुनिक तथा दूर तक मार करने वाले एफ-16 लड़ाकू विमान तथा अन्य शस्त्रास्त्रों की सप्लाई करने पर आमादा है। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनेक बार अमेरिकी प्रशासन को भारतीय उपमहाद्वीप में शस्त्रीकरण की होड़ शुरू करने के विरुद्ध आगाह किया है किन्तु अमेरिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि अमेरिकी हथियारों के कारण पाकिस्तान के फौजी आसक्तों का दिमाग नहीं फिरता तो शायद वे पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) की जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा लोकतन्त्री अधिकारों का दमन करने के लिए टैंको और मशीनगनों का इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान के खण्डित होने तथा स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में बंगलादेश के उदय के पीछे अनेक कारण थे। पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता भी इनमें से एक थी।

अमेरिका पुनः पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों तथा अन्य फौजी साज-सामानों की सप्लाई कर रहा है। कुछ लोगों का विश्वास है कि अन्तर्गतत्वा इससे पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का भविष्य क्या है, हम इस बारे में कोई अटकल नहीं लगाना चाहते हैं किन्तु इतना निश्चित है कि अमेरिका से मिले एफ-16 लड़ाकू विमानों तथा हथियारों का इस्तेमाल वह भारत के विरुद्ध ही करेगा। भारत का इस पर चिन्तित होना तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा देश की जनता व विश्व के नेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना स्वाभाविक ही है। भारत के नेता और आम जनता कभी भी नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान विलुप्त हो जाए। पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता भारत के हित में भी है।

भारत व अमेरिका के बीच सारे मतभेद समाप्त हो जाएँगे, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी तो मतभेद के अनेक मुद्दे हैं। तारापुर परमाणु सयन्त्र के लिए ईंधन की सप्लाई के लिए दोनों देशों के बीच हुए समझौते को अमेरिका ने जिम भोडे ढग से तोड़ा है उससे द्वि-पक्षीय सम्बन्ध सुधारने में मदद नहीं मिलती है। अमेरिका यदि नई परिस्थितियों में भारत को परमाणु ईंधन नहीं दे सकता है या नहीं देना चाहता है तो कम-से-कम आपसी बातचीत द्वारा शालीन ढग से समझौते को रद्द करने पर तो सहमति हो सकती है।

भारतीय संविधान बहुदलीय लोकतन्त्र में विश्वास करता है। उसमें एक दलीय मानसंवादी शासन प्रणाली के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत की सोवियत

रूस के साथ मैत्री जरूर है, व्यापक आर्थिक सहयोग भी है किन्तु रूस के साथ भारत किसी सैन्य सन्धि में बँधा हुआ नहीं है। अमेरिकी प्रशासन को शिङ्कायत हो सकती है कि भारत ने कम्युनिज्म में हेग सामरिन को सरकार को तथा अफगानिस्तान में बाबरक कारमेत की सरकार को मान्यता प्रदान कर सही मायनों में निर्गुट विदेश नीति का अनुसरण नहीं किया है। अमेरिका चाहता है कि भारत सरकार अफगानिस्तान में रूस के सैन्य हस्तक्षेप की खुलकर आलोचना और विरोध करे। कम्युनिज्म तथा अफगानिस्तान के प्रश्नों पर भारत सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है उस पर भारत तथा रूस के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की शायद छाया पड़ी हो। या यो कह सकते हैं कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सामने रख कर ही इन विवाद-ग्रस्त प्रश्नों पर अपनी नीति का निर्धारण किया है।

भारत सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि अपने राष्ट्रीय हितों को तजरन्दाज कर वह विदेश नीति निर्धारित करेगी। भारत और रूस के सम्बन्धों का लम्बा इतिहास है। प्रश्न कश्मीर का हो, सैन्य सहायता का हो या बंगलादेश के मुक्ति संग्राम का, भारत को रूस से नाजुक मौकों पर मदद मिली है। पाकिस्तान अमेरिकी मदद से पुनः भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। चीन हजारों वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। इस अव्यवस्था को भारत बंध करार दे दे, इस लक्ष्य को सामने रखकर वह पूरे अफ़्गानिस्तान प्रदेश पर दावा कर रहा है। अफ़्गानिस्तान पर अपना दावा वापस लेकर अक्सार्द चीन पर अपने कब्जे पर वह भारत से स्वीकृति की मुहर लगवाना चाहता है।

अमेरिकी प्रशासन की अपेक्षा है कि भारत चीन और पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधारे। रूस के साथ भारत की मैत्री उमे सटकती है। भारत को आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय हितों पर यदि अमेरिका गौर करे तो भारत के प्रति अपनी रीति-नीति में त्रुटियाँ हटाने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में सुधार की प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है।

अमेरिकी विदेश मंत्री श्री अलेक्जेंडर हेग की भारत-यात्रा से उन्हें भारत की विज्ञाप परिस्थितियों को समझने में सहायता मिलेगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। भारत हमी खेम में है, यह निष्कर्ष जितना गलत है उतना ही व्यापहारिक होगा कि भारत को अमेरिकी शिबिर में लीजकर लाया जा सकता है। परमाणु हथियारों के ज्वालामुखी पर बँटे विश्व को ऐसे भारत की जरूरत है जो मही अर्थों में निर्गुट हो, जो महाशक्तियों के बीच टकराव टालने में सहायक बन सकता हो।¹

अमेरिका और मध्य अमेरिकी राज्य :

अलसल्वाडोर : निर्णायक संघर्ष के दौर में

समुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अमेरिकी राज्यों के साथ जो सम्बन्ध है वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक विचार्यों के लिए अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण

है क्योंकि अमेरिका जिस विश्व नीति पर इस समय चल रहा है उसका परीक्षण वह सैकड़ों वर्षों से इन्हीं राज्यों में करता रहा है। अलसल्वाडोर नामक एक मध्य अमेरिकी राज्य के वर्तमान निर्माणक सवर्ण के सन्दर्भ में श्री शारदेन्दु ने अपने एक लेख में मध्य अमेरिकी राज्यों के प्रति समुक्त राज्य अमेरिका की नीति पर अच्छा प्रकाश डाला है¹—

“पश्चिम एशिया की भाँति समुक्त राज्य अमेरिका का पृष्ठ प्रदेश भी राजनीतिक दृष्टि से विश्व के अस्थिरतम क्षेत्रों में से है। इस क्षेत्र में मध्य अमेरिका के अनेक छोटे-छोटे राज्य हैं जिन्हें कॅरीबियन खाड़ी के तट पर बसा होने के कारण कॅरीबियन राज्य कहा जाता है। सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिका भी इसी क्षेत्र में है। इन राज्यों की लेटिन अमेरिकी राज्य और केले की बहुतायत के कारण ‘बनाना रिपब्लिकस’ भी कहा जाता है। सच कहा जाए तो इनकी राजनीति केले के छिपके की ही तरह फिसलती है।

कहने को तो ये राज्य रिपब्लिक अथवा गणतन्त्र कहे जाते हैं किन्तु वास्तव में वे निकृष्टतम तानाशाही के पालने हैं। आए दिन वहाँ सैनिक आगितियाँ होती रहती हैं, जिनमें सेना का एक जनरल दूसरे जनरल से सत्ता हथिया लेता है। कभी-कभी नाम मात्र को किसी राज्य में घरेलू सरकार भी स्थापित हो जाती है, जो प्रायः अल्पजीवी होती है।

इन राज्यों का सबसे बड़ा अपराध या दुर्भाग्य यह है कि वे पूर्वी गोलार्ध से कटे हुए समुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के पड़ोसी हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी कम्पनियों का पूर्ण नियन्त्रण है। वे इनकी प्राकृतिक सम्पदाओं और कृषि-उत्पाद दोनों का खुलकर दोहन कर रही हैं। इनकी सरकारों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर रहता है कि वे उक्त कम्पनियों के दोहन-कार्य में कहीं तक सहायक होती हैं। उनके हितों पर चोट पहुँचते ही, अथवा उनको खतरा पैदा होते ही, अमेरिकी सरकार और सी आई ए की पूरी मशीनरी गतिशील हो उठती है और बाधक तत्वों का सफाया करा दिया जाता है। चिली के एलेन्दे, पार्नेटाइना के पॅरो, घादि इसके उदाहरण हैं।

अमेरिका जिस विश्व-नीति पर इस समय चल रहा है, इसका परीक्षण यह सैकड़ों वर्षों से इन्हीं राज्यों में करता रहा है। एक वाक्य में उसकी नीति यह है कि—जहाँ तक अमेरिकी हथियार, सेनाएँ और सहायता पहुँच सकती है वहाँ तक उसका प्रभाव-क्षेत्र है और उरा प्रभाव-क्षेत्र को बनाए रखने के लिए उसे उचित-अनुचित कुछ भी करने का अधिकार है।

मध्य तथा दक्षिण अमेरिकी राज्यों को तो वह किसी मूल्य पर अपने प्रभाव-क्षेत्र से नहीं निकलने दे सकता है। पनामा नहर जैसी उसकी जीवन-रेखा इसी क्षेत्र में है। इसीलिए यदि किसी राज्य की सरकार कुछ स्वतन्त्रता दिखाने का प्रयत्न करती है अथवा किसी राज्य की जनता अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती है,

संघर्ष करती है, तो उसमें अमेरिका को अपने अस्तित्व के लिए खतरा नजर आने लगता है। यही कारण है कि इन राज्यों के जन-संघर्षों में अमेरिका सदा तानाशाहियों का पक्ष लेता रहा है और जो तानाशाही जितनी निरकुश होती है, उसे अमेरिका का उतना ही अधिक समर्थन प्राप्त होता है। इसी नीति का पालन हम अमेरिका को अन्य क्षेत्रों—पाकिस्तान, थाईलैण्ड, कम्पूचिया, वियतनाम, पश्चिम एशिया आदि में करते हुए पाते हैं।

नई चेतना

लेकिन आज स्थिति यह है कि अपनी सम्पूर्ण शक्ति और प्रभुत्व के बावजूद अमेरिका के लिए इतिहास-चक्र को रोकना या उलटना अत्यन्त कठिन हो रहा है। मधुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि लेटिन अमेरिकी देशों का अलग-थलग टूटा है और वहाँ की जनता में नई चेतना आई है। इसका एक प्रमाण यह है कि अधिकाधिक लेटिन अमेरिकी देश निर्गुट आन्दोलन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। निर्गुट आन्दोलन के देशों की दो महत्वपूर्ण बैठकें हवाना (क्यूबा) और काराबास (वेनेजुएला) में हो चुकी हैं।

इस समय मध्य अमेरिका के जो देश सबसे अधिक विषय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वे हैं अलसल्वाडोर तथा निकारागुआ।

क्यूबा के कास्त्रो के नेतृत्व में वामपक्षी तत्त्वों की विजय से अमेरिका के एक दुर्गम में सबसे पहली दरार पड़ी। इसके बाद क्यूबा को सोवियत संरक्षण मिल जाने के कारण और कुछ अमेरिका को क्यूबा की जनता से वांछित समर्थन न मिल पाने के कारण अमेरिका द्वारा कास्त्रो को हटाये जाने और इस दरार को भरने के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं। निस्सन्देह क्यूबा अमेरिका की आँखों में निरन्तर कटि की तरह चुभता रहा है। क्यूबा में वामपक्षी तत्त्वों की सफलता ने अन्य लेटिन अमेरिकी राज्यों में भी वामपक्षी लोकतन्त्रों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी है।

निकारागुआ एक अन्य मध्य अमेरिकी राज्य है जहाँ के अलोकप्रिय तानाशाह सोमोज़ा को हटाकर वामपक्षी सादनस्ता दल ने शासन पर अधिकार कर लिया है। सी आई ए. ने इस शासन को उखाड़ फेंकने और सोमोज़ा को पुनः सत्ता में लाने के लिए एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत होडूरा स्थित सोमोज़ा समर्थक नेशनल गार्ड्स को अमेरिका से पूरी सहायता मिल रही है। उन्होंने निकारागुआ में छापामार कार्यवाहियाँ कर वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पुलों को उड़ा भी दिया है। फलस्वरूप निकारागुआ में तीस दिन के लिए आपावस्थिति की घोषणा कर दी गई।

जीवन-मरण का संघर्ष

अमेरिका का निकारागुआ पर आरोप है कि वह क्यूबा और सोवियत संघ में बड़ी मात्रा में हथियार मँगारकर अलसल्वाडोर के वामपक्षी विद्रोहियों की सहायता कर रहा है। निकारागुआ सरकार ने बार-बार इसका खण्डन किया है। अलसल्वाडोर

इस समय एक सूती गृहयुद्ध के दौर से गुजर रहा है। वहाँ की घोर दक्षिणपंथी दुम्रात सरकार जीवन-मरण संघर्ष से जूझी हुई है। यद्यपि वहाँ राष्ट्रपति के नए चुनाव होने में एक महीने का समय भी नहीं रह गया है तथापि उनके परिणामों का इस गृह-युद्ध पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव एक नाटक से अधिक कुछ नहीं हो सकते। वामपंथी नेताओं ने उसका बहिष्कार किया हुआ है क्योंकि वे जानते हैं कि चुनाव क्षेत्र में कूदते ही उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा।

दुम्रात सरकार के दमन की कहानी उन आंकड़ों से बोलती है, जो अमेरिका में अलसल्वाडोरवासियों के लिए नियुक्त कानूनी सहायता कार्यालय ने प्रकाशित किए हैं। 12 जनवरी, 1981 को वहाँ फौजी कानून की घोषणा के बाद 1981 में 12,501 गैर-मैनिक मारे गए। 2127 नागरिकों को कपड़ों के दौरान गोली के घाट उतार दिया गया। कार्यालय ने जो प्रमाण एकत्र किए हैं उनके अनुसार 9,239 नागरिकों की हत्या के लिए सुरक्षा सैनिक ही जिम्मेदार हैं।

मजेदार बात यह है, विदेशी सहायता विधेयक में राष्ट्रपति रीगन ने प्रमाण-पत्र दिया है कि अलसल्वाडोर सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानव-अधिकारों का पालन करने के लिए जोरदार प्रयत्न कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि यदि अलसल्वाडोर में दुम्रात सरकार का पतन हो गया तो फिर अन्य मध्य और दक्षिण अमेरिकी राज्यों में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया होगी।

यह बात अन्तःअमेरिकी मामलों के लिए सहायक विदेजमन्त्री थॉमस एण्डर्स के इन शब्दों से भी स्पष्ट है—“अलसल्वाडोर में मध्य अमेरिकी के लिए निर्णायक मार्ग जारी है। यदि निकारागुआ के बाद अलसल्वाडोर पर भी एक उप-अल्पमन का अधिकार हो जाता है तो मध्य अमेरिका में कौन भय के बिना रह सकेगा? पनामा नहर, समुद्री मार्ग, तेल सप्लाय जैसे अमेरिका के प्रमुख सामरिक हितों को संकट पैदा होने में फिर कितनी देर लगेगी?”

अमेरिका अलसल्वाडोर के मामले को इतना तूल दे रहा है, इसका एक और भी कारण बताया जाता है। अमेरिकी बजट की हालत बहुत खस्ता है। घोर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन सदस्य भी प्रतिरक्षा व्यय में कटौती की माँग कर रहे हैं। अतः अमेरिकी प्रशासन को सैनिक व्यय में वृद्धि की माँग स्वीकार कराने के लिए कोई बहाना चाहिए। इससे अच्छा बहाना और कौन हो सकता है कि खतरा उसके पिछवाड़े में ही आ पहुँचा है?

अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में अमेरिका हर प्रकार के झूठ का सहारा ले रहा है। इसके अनेक दिलचस्प उदाहरण सामने आए हैं।

परराष्ट्र विभाग ने एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया था जिसका क्यूबा, निकारागुआ और अलसल्वाडोर के विद्रोहियों के बीच हथियार-सम्बन्ध दिखाना था। ऐसा दावा किया गया कि वह छायाकारी से पकड़े गए कागजों पर आधारित है।

उनका मित्र देशों में काफी प्रसार भी किया गया लेकिन चार महीने बाद ही एक अमेरिकी अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसमें भारी गलतियाँ हैं और उससे सही निष्कर्षों को निकालना सम्भव नहीं है।

कुछ दिन पूर्व परराष्ट्र विभाग ने एक 19-वर्षीय निकारागुअन छापामार ओलेंदो जोसनादेनशिलास एस्पिनोजा को पत्रकारों के सामने पेश किया जिससे वह बना सके कि किस प्रकार उसे क्यूबा तथा इथियोपिया में छापामारी के लिए प्रशिक्षित किया गया था लेकिन जो कुछ उसने बताया वह ठीक उसका उल्टा था। उसने कहा कि, 'मैं कभी क्यूबा या इथियोपिया नहीं गया। स्वेच्छा से छापामार सैनिकों में शामिल हुआ था।' उसने उत्पीड़न की कहानियाँ भी सुनाईं।

इसके भी अधिक रोमांचकारी अनुभव एक ब्रिटिश यात्री के हैं जो घूमना हुआ अलमल्वाडोर में पहुँच गया था और छापामारी के सन्देह में उसे वहाँ छाठ घण्टे बन्द रहना पड़ा था। इस बीच उसे भारी यन्त्रणाएँ सहनी पड़ी।

मित्र भी समर्थक नहीं

कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिका के यूरोपीय मित्र भी उसकी मध्य-अमेरिकी नीति से सहमत नहीं हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मितेरां तो विशेष रूप से इस नीति का चुनकर विरोध कर रहे हैं और उन्होंने निकारागुआ की रक्षा के लिए कुछ हथियार बेचना भी स्वीकार कर लिया है।

स्वयं अमेरिका में रीगन प्रशासन की इन नीतियों का भारी विरोध हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में 1977 से 1979 तक अमेरिकी राजदूत एड्रू यंग ने तो यहाँ तक कहा कि इस नीति ने अमेरिका को बीस वर्ष पीछे धकेल दिया है। उन्होंने किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए अलमल्वाडोर के सचट के राजनीतिक हल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय देखरेख में बातचीत का सुझाव दिया।

धनेक अमेरिकी पक्षों ने यह आशंका प्रकट की है कि यदि रीगन प्रशासन ने अपनी वर्तमान नीतियाँ जारी रखी तो अलमल्वाडोर अमेरिका के लिए एक और वियतनाम बन सकता है।

कुछ चर्चा अन्य सेंटिन अमेरिकी देशों की कर लेना भी अप्रासंगिक नहीं होगा।

ग्वाटेमाला में हाल में राष्ट्रपति-पद के चुनाव हुए हैं जिनमें उप-दक्षिण-पथी मत्तारूटु गुट के उम्मीदवार प्रतिरक्षा मन्त्री जनरल गुएवारा को विजयी घोषित किया गया है। ग्वाटेमाला की स्थिति भी अलमल्वाडोर में बेहतर नहीं है और इन चुनावों का बहिष्कार किया ही। जनरल गुएवारा के तीन दक्षिणपथी प्रतिद्वन्द्वियों और उनके समर्थकों के चुनावों में गड़बड़ी के विरोध में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर उनके साथ भी भारी दुर्व्यवहार किया गया। वर्तमान शासन उदार दक्षिणपथियों को भी खतरनाक तत्त्व समझता है।

पदाधीन राष्ट्रपति जनरल गार्गिया के बारे में 'वाशिंगटन पोस्ट' ने लिखा है—“उन्होंने चार वर्षों तक अपने से बायपक्षी राजनीतिक नेताओं की हत्याओं, सौंप, निर्वासन और डराने-धमकाने के बल पर शासन किया है। निर्विवाद रूप से अधिकांश सरकारी हाथों द्वारा। हजारों व्यक्ति मौत के घाट उतारे गए हैं। उन्होंने अपने शासन के लिए दुनिया का सम्भवतः सबसे खूनी शासन होने का नाम कमाया है।” सरकारी मौत के दर्से प्रोमत्तन तीन सौ व्यक्तियों को प्रति मास डिकाने लपते रहते हैं। कहना न होगा कि रीगन प्रशासन इस शासन का भी धर्म-पिता रहा है।

“सूरीनाम में गत सप्ताह एक मैजिक ज़ान्ति का असफल प्रयत्न किया गया जिसका नेतृत्व इंडोनेशियाई सेनाधिकारियों ने किया था। उसमें एक साजेंट मेजर विलफ्रेड हाफर को गोली से उड़ा दिया गया। अन्य विद्रोही नेताओं की खोज जारी है। तीन भगदड़ें भी पकड़े गए हैं। कोलम्बिया में सेना ने राजधानी बोगोटा पर अधिकार कर लिया है। ये सभी इस क्षेत्र की अस्थिर राजनीति के परिचायक हैं।”



जनवरी 1977 से मार्च 1982 तक की महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की झलक

जनवरी, 1977

पाँच अफ्रीकी राष्ट्रपतियों की लुमाका में शिखर-वार्ता ।

9 जिम्बाब्वे मुक्ति मोर्चे को पूर्ण समर्थन देने का प्रस्ताव पारित कर लुमाका शिखर-सम्मेलन समाप्त ।

18 श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा भारत में मार्च में आम चुनाव की घोषणा ।

20 जिम्मी कार्टर द्वारा अमेरिका के 29वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण ।

31 एण्ड्रू यंग द्वारा संयुक्तराज्य अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण ।

फरवरी, 1977

1 अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया से धीरे-धीरे सेना हटाने का निश्चय ।

16 मुहम्मद दाऊ अकगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित ।

मार्च, 1977

7 काहिरा में अरब-अफ्रीकी देशों के शिखर-सम्मेलन में 60 देश सम्मिलित ।

20 तुर्की और सोवियत संघ में मैत्री-ममझौता । चीन द्वारा शक्तिशाली नौ-सेना निर्माण करने का निश्चय ।

24 भारत में मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता निर्वाचित और प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण ।

अप्रैल, 1977

9 रुम और क्यूबा द्वारा दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष का समर्थन ।

21 जनरल जियाउरहमान बंगलादेश के नए राष्ट्रपति ।

27 भारत और सोवियत संघ में तीन समझौतों पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर । जनरल टिक्का खान पाकिस्तान के नए प्रतिरक्षा मंत्री ।

मई, 1977

7 पाकिस्तान को अमेरिका से दो बिल्वंमक प्राप्त ।

19 अमेरिका तथा सोवियत संघ सहित 31 देशों द्वारा कृत्रिम मौसम का शस्त्र के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध ।

20 हवियारों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर की छः मूखी योजना ।

23 बेगिन द्वारा अरब अधिकृत क्षेत्र को 'मुक्त क्षेत्र' बनाना ।

जून, 1977

- 4 अमेरिका और क्यूबा राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने पर सहमत ।
- 7 प्रधान मंत्री देसाई और विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लेने के लिए तन्दन रवाना ।
- 8 तन्दन में राष्ट्रकुल शिखर-सम्मेलन शुरू ।
- 14 चीन द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया के समझौते को अवैध ठहराना ।
- 15 तन्दन में राष्ट्रकुल सम्मेलन की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति जारी ।
- 16 लियोनिद ब्रेझेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित ।
- 19 वाटरगेट काण्ड समाप्त ।
- 21 लिटुड के नेता बेटिंगन द्वारा इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण ।
- 27 मक्का का स्वतंत्र जिवूती को स्वाधीनता प्राप्त ।
- 30 यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा फिलिस्तीनियों के लिए पृथक् राज्य का समर्थन ।

जुलाई, 1977

- 5 पाकिस्तान में रक्तहीन शान्ति । मुद्रा सहित सभी राजनीतिक नेता गिरफ्तार और फौजी कानून लागू ।
- 20 सुरक्षा परिषद् द्वारा वियतनाम को संयुक्तराष्ट्र का सदस्य बनाने का अनुमोदन ।
- 28 चीन द्वारा उद्जन बम का विस्फोट ।

अगस्त, 1977

- 11 सोवियत संघ और चीन में सीमा वार्ता । अमेरिका की दक्षिण कोरिया को 190 करोड़ डॉलर की सहायता ।
- 14 विश्व के कम्युनिस्टों में भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए मार्शल टीटो की सोवियत संघ और चीन की यात्रा ।
- 15 अरब-इजरायल संघर्ष की समाप्ति के लिए अमेरिका द्वारा घाठ सूत्री योजना प्रस्तुत ।

सितम्बर, 1977

- 1 रोडेशिया के चुनाव में इयान स्मिथ के रोडेशियाई मोर्चे को भारी बहुमत प्राप्त ।
- 6 मास्को में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डॉ. वातदहीम और सोवियत विदेशमंत्री ग्रेमिन्को द्वारा विश्व में निःशस्त्रीकरण पर जोर ।
- 21 संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 32वें अधिवेशन के प्रथम पर वियतनामी समाजवादी गणतन्त्र का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश ।

अक्टूबर, 1977

- 1 वाशिंगटन में भारत के विदेश मंत्री द्वारा तब तक परमाणु विस्तार निरोधक सन्धि पर हस्ताक्षर न करने की घोषणा जब तक सभी देश इस प्रकार के अस्त्रों को समाप्त करने की कार्यवाही न करें ।

7 चीन और सोवियत संघ के बीच पिछले आठ वर्षों में पहली बार नौ-मैत्रिक समझौता सम्पन्न ।

26 नेवादा भरस्वेल में अमेरिका द्वारा परमाणु बम विस्फोट ।

नवम्बर, 1977

1 सुरक्षा परिषद् में दक्षिण अफ्रीका विरोधी प्रस्तावों पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा निषेधाज्ञा के अधिकार का प्रयोग ।

2 अमेरिका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन से हटना ।

10 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादान द्वारा पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापना के लिए इजरायल जाने की घोषणा ।

19 यरूशलम पहुँचने पर अनवर सादान का भव्य स्वागत ।

21 सादान और बेगिन द्वारा युद्ध न करने का एलान ।

दिसम्बर, 1977

1 सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण ।

4 पासिर अराफ़त के नेतृत्व में सभी फिलिस्तीनी गुटों में एकता ।

7 मिस्र द्वारा सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, हंगरी आदि के सांस्कृतिक केंद्रों को बन्द करने के आदेश ।

25 इजरायली प्रधानमंत्री श्री बेगिन और मिस्री राष्ट्रपति सादान के बीच इस्माइलिया में शिखर वार्ता ।

26 सादान-बेगिन की समझौता वार्ता विफल, मुख्य बाधा फिलिस्तीन समस्या का हल न ढूँढ़ पाना ।

जनवरी, 1978

1 अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जिम्मी कार्टर का भारत आगमन ।

3 भारत-अमेरिका मयुक्त घोषणा : तीन कसरतों और घोषणाओं पर हस्ताक्षर ।

11 बेगिन द्वारा पश्चिमेशिया पर पाँच सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत ।

फरवरी, 1978

1 30 देशों का निरस्त्रीकरण सम्मेलन जिनेवा में शुरू ।

मार्च, 1978

4 हुषा कुषा फंड. चीन के पुन. प्रधान मंत्री निर्वाचित ।

5 श्रीलंका अब श्रीलंका लोकतान्त्रिक समाजवादी गणराज्य घोषित ।

8 चीन द्वारा नया सविधान प्रकाशित ।

15 चीन द्वारा परमाणु विस्फोट ।

22 वाशिंगटन में कार्टर और बेगिन में पश्चिमेशिया समस्या पर वार्ता ।

अप्रैल, 1978

4 अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा म्यूटान बम बनाने की योजना समाप्त करने का निर्णय ।

19 फ्रांस द्वारा न्यूट्रान बम का परीक्षण ।

25 सोवियत संघ द्वारा न्यूट्रान बम न बनाने का एलान ।

मई, 1978

14 चीन द्वारा सोवियत संघ को युद्ध की धमकी ।

17 हवाना (क्यूबा) में गुट-निरपेक्ष देशों का ब्यूरो सम्मेलन शुरू ।

28 नेपाल और चीन में गीगा सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर ।

जून, 1978

9 प्रधानमन्त्री देसाई द्वारा संयुक्त-राष्ट्र महासभा में पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए चार सूत्री योजना ।

12 मेजर जनरल जियाउरहमान द्वारा बंगलादेश के राष्ट्रपति पद की शपथ ।

23 सोवियत संघ का तुर्की से तेल समझौता ।

चीन द्वारा यूरोप में आधुनिक हथियारों की खरीद का अभियान ।

जुलाई, 1978

23 इजरायल द्वारा सिनाइ नगर लौटाने से इन्कार । अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कड़े कदम उठाने का निर्णय ।

26 वेलप्रेड सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की विभिन्न व्याख्याएँ और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अस्त्र सहायता पर रोक की अपील ।

30 वेलप्रेड में गुट-निरपेक्ष विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन समाप्त ।

मिस्र के राष्ट्रपति अन्नबर सादात द्वारा इजरायल से शान्ति-वार्ता भग ।

अगस्त, 1978

16 चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु की जानकारी देने का प्रस्ताव ।

सितम्बर, 1978

6 चीन द्वारा अप्रैल, 1979 में चीन-सोवियत सन्धि रद्द करने का निश्चय ।

7 अमेरिका और सोवियत संघ में अस्त्र प्रसार निरोध जार्न (मास्ट) मास्को में शुरू ।

16 जिया उल-हक अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ।

18 कैम्प डेविड चर्चा सफल तथा मिस्र और इजरायल शान्ति-समझौता करने पर सहमत ।

24 चार अन्व देशों द्वारा मिस्र से राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद । इजरायली मन्त्रिमण्डल द्वारा कैम्प डेविड समझौते का अनुमोदन ।

30 प्रशान्त महासागर में स्थित तुवालु द्वीप को ब्रिटेन द्वारा स्वाधीनता प्रदान ।

अक्तूबर, 1978

2 क्लिस्तीनियों द्वारा कैम्प डेविड समझौते की आलोचना ।

10 संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेशमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अपने हिन्दी भाषण में निरस्त्रीकरण के लिए 6 सूत्री योजना प्रस्तुत ।

23 चीन-जापान शान्ति-समझौते का दोनों देशों द्वारा अनुमोदन ।

नवम्बर, 1978

- 4 मास्को में सोवियत संघ और वियतनाम में मैत्रि सम्झौते पर हस्ताक्षर ।
- 26 फ्रांस द्वारा चीन को परमाणु सयंत्र बेचने पर अमेरिका की छूट ।
- 29 सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण ।
- 30 पूर्व और पश्चिम जर्मनी द्वारा सीमा सम्झौते पर हस्ताक्षर ।

दिसम्बर, 1978

- 11 ओस्लो में मेनाहिम बेगिन और अनवर सादात को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान ।
- 16 अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा पहली जनवरी, 1979 से चीन से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा ।

जनवरी, 1979

- 1 अमेरिका और चीन में राजनयिक सम्बन्ध स्थापित और वुडकाक पीकिंग में प्रथम अमेरिकी राजदूत ।
- 16 फ्रांस और चीन द्वारा परमाणु सहयोग सम्बन्धी सम्झौते पर हस्ताक्षर ।

फरवरी, 1979

- 1 निर्बामित धार्मिक नेता अयातुल्ला खुर्मेनी को पेरिस में तेहरान लौटने पर भव्य स्वागत ।
- 12 अटल बिहारी वाजपेयी का पीकिंग आगमन ।
- 17 चीन का वियतनाम पर हमला ।
- 19 बंगलादेश के चुनाव में राष्ट्रपति जियाउर्रहमान की बंगलादेश राष्ट्रीय पार्टी को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त । ईरान द्वारा अन्तिम 67 इजरायली निष्कासित ।

मार्च, 1979

- 3 चीन द्वारा वियतनाम से अपनी सेनाएँ वापस बुलाने का फैसला ।
- 4 ब्रिटेन चीन द्वारा 14 अरब डॉलर व्यापार सम्झौते पर पीकिंग में हस्ताक्षर ।
- 7 कार्टर का बाहिरा पहुँचने पर भव्य स्वागत ।
- 10 मिस्री नेताओं से वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का तेलअवीव (इजरायल) आगमन ।
- 12 ईरान और पाकिस्तान द्वारा 'मेटो' से सम्बन्ध विच्छेद ।
- 15 तुर्की, दूरग. भी. केन्द्रीय, मन्त्रि, मण्डल, (मैटो), मे. सम्बन्ध विच्छेद ।
- 21 शान्ति-मन्त्रि के बाद इजरायल को अमेरिका द्वारा तीन अरब डॉलर सहायता का प्राश्चामन ।
- 26 वाशिंगटन में मिश्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजरायल प्रधानमन्त्री मेनाहिम बेगिन द्वारा शान्ति-मन्त्रि पर हस्ताक्षर ।

अप्रैल, 1979

25 मिस्र और इजरायल द्वारा शान्ति सम्बन्धी दस्तावेजों का प्रादान-प्रदान ।

मई, 1979

8 रूस और अमेरिका द्वितीय अस्त्र परिसीमन सन्धि के लिए सहमत ।

25 इजरायल द्वारा सिनाई की राजधानी अल अरिश मिस्र द्वारा सौंपा जाना ।

27 मिस्र और इजरायल दोनों देशों के बीच खुले आगमन के लिए सहमत ।

29 रोडेशिया में पहले अश्वेत प्रधानमन्त्री बिशप मुजोरेवा द्वारा शपथ ग्रहण ।

जून, 1979

10 प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई का ताशकन्द आगमन ।

18 विद्युता में अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेज्नेव द्वारा साल्ट-2 समझौते पर हस्ताक्षर ।

जुलाई, 1979

6 हवाना के गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अन्वर सादात को निमन्त्रण ।

21 मोनोराविया में अफ्रीकी एक्ता संगठन के शिखर सम्मेलन में रोडेशिया की नई सरकार को मान्यता देने से इन्कार ।

31 लुसाका में राष्ट्रकुल देशों का शिखर सम्मेलन शुरू ।

अगस्त, 1979

7 लुसाका शिखर सम्मेलन रोडेशिया पर नई योजना का अनुमोदन न कर समाप्त ।

सितम्बर, 1979

3 गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में 12 और सदस्य शामिल ।

5 हैफा में मिस्र के राष्ट्रपति अन्वर सादात और इजरायल के प्रधानमन्त्री मेनाहिम बेगिन में तेल अबीव और सिनाई पर समझौता ।

8 चीन द्वारा कई यूरोपीय देशों से भारी मात्रा में अस्त्रों की खरीद ।

10 रोडेशिया पर लन्दन में संवैधानिक सम्मेलन शुरू ।

19 संयुक्तराष्ट्र महासभा द्वारा पोतपोत की कंबुजिया सरकार को मान्यता प्रदान ।

22 चीन द्वारा प्रक्षेपास्त्र परीक्षण ।

23 सोवियत संघ के सम्बन्ध सुधार के लिए चीन के एक प्रतिनिधि भण्डल का मास्को आगमन ।

28 बंगलादेश द्वारा परमाणु प्रसार विरोधी सन्धि पर हस्ताक्षर ।

29 बर्मा द्वारा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से सम्बन्ध विच्छेद ।

अक्टूबर, 1979

3 ब्रिटेन के विदेशमन्त्री लॉर्ड केरिग्टन द्वारा रोडेशिया के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत ।

- 12 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हुआ कुओ फेड. पहली बार पश्चिम यूरोपीय देशों की यात्रा पर रवाना ।
- 15 ईरान में अयातुल्ला खुमैनी को सर्वोच्च शासकीय सत्ता प्रदान ।
- 23 हुआ द्वारा जर्मनी ने एकीकरण को विश्व-शान्ति के लिए हितकर बताना ।
- 27 रोडेशिया के प्रधानमंत्री विशेष मुजोरेबा द्वारा लन्दन प्रस्ताव स्वीकार ।
- 28 सेंट विसेंट को स्वाधीनता प्रदान ।

नवम्बर, 1979

- 2 लन्दन में ब्रिटेन और चीन में वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर ।
- 11 जिम्मी कार्टर द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अमेरिका में रहने वाले ईरानियों को स्वदेश भेजने की धमकी ।
- 12 अमेरिका द्वारा ईरान से तेल आयात करने पर प्रतिबन्ध ।
- 14 कार्टर द्वारा अमेरिकी बैंको में जमा ईरानी सम्पत्ति की नाकेबन्दी ।
- 15 इजरायल द्वारा माउन्ट सिनाई का क्षेत्र मिस्र को वापस, रोडेशिया पर देशभक्त मोर्चे द्वारा ब्रितानी प्रारूप स्वीकार ।
- 19 ईरान द्वारा 13 और अमेरिकी बन्धक रिहा ।
- 22 ईरान द्वारा पाँच और अमेरिकी बन्धक रिहा ।

दिसम्बर, 1979

- 1 ईरान के बहिष्कार के बावजूद समुक्तराष्ट्र सुरक्षा-परिषद् द्वारा ईरान संकट पर विचार-विमर्श ।
- 2 पीकिंग में सोवियत सघ और चीनी अधिकारियों में सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने पर वार्ता ।
- 4 ईरान ने जनमत संग्रह के फलस्वरूप अयातुल्ला खुमैनी आजीवन राजनीतिक 'संस्थापक' नियुक्त, बर्मा और बंगलादेश में सीमा समझौता ।
- 5 लन्दन में रोडेशिया समझौते की घोषणा ।
- 8 पीकिंग में जापानी प्रधानमंत्री ओहिरा द्वारा चीन से सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने का एलान ।
- 11 रोडेशिया की ससद् भंग ।
- 12 रोडेशिया के विरुद्ध ब्रितानी आर्थिक प्रतिबन्ध समाप्त ।
- 13 अमेरिका द्वारा 183 ईरानी राजनयिकों को वापस जाने का आदेश ।
- 14 ईराक का ईरान पर सशस्त्र आक्रमण ।
- 15 अमेरिकी सरकार का सुरक्षा व्यय में बढोत्तरी करने का फैसला, नेटो द्वारा रूस को सशस्त्र नियन्त्रण सम्बन्धी पाँच सूत्री प्रस्ताव ।
- 17 12 वर्ष बाद रोडेशिया के साथ व्यापार और व्यवसाय पर से अमेरिकी सरकार का प्रतिबन्ध समाप्त ।
- 22 समुक्तराष्ट्र द्वारा रोडेशिया के विरुद्ध 14 वर्षीय प्रतिबन्ध समाप्त ।
- 27 अफगानिस्तान में तालिब और राष्ट्रपति हकीजुल्ला अमीन सत्ताच्युत ।

जनवरी, 1980

- 1 ईरानी नेताओं से बातचीत करने के लिए संयुक्तराष्ट्र महासचिव डॉ नुतं वास्दहीम का तेहरान आगमन ।
- 8 अमेरिकी द्वारा 17 रूसी निष्कासित; संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पर रूस के वीटो के अधिकार का प्रयोग ।
- 13 अफगानिस्तान में सोवियत पद्धति के अनुसार सरकार का गठन ।
- 14 पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर की अमेरिकी सहायता; ईरान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस द्वारा अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग ।
- 15 संयुक्तराष्ट्र महासभा द्वारा अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित ।
- 20 चीन द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहयोग का आश्वासन ।
- 28 अमेरिका द्वारा 1,000 अरब डॉलर के प्रतिरक्षा बजट की योजना ।

फरवरी, 1980

- 5 वनीसदर द्वारा ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण ।
- 14 अमेरिका द्वारा यूरोपीय क्षेत्रों में अस्त्र मग्नहीन करने की योजना ।
- 26 मिस्र और इजरायल में राजदूतों का आदान-प्रदान ।

मार्च, 1980

- 1 फ्रांस द्वारा परमाणु परीक्षण ।
- 14 पाकिस्तान में चीनी सैनिक प्रतिनिधि-मण्डल का आगमन । 18 अप्रैल को रोडेशिया को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान किए जाने की ब्रिटेन गवर्नर लॉर्ड सीमेस द्वारा घोषणा ।
- 22 अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बबरक कारमाल द्वारा ब्रिटेन की तटस्थीकरण योजना अस्वीकार ।
- 24 ईरान के अपदस्य शाह का काहिरा आगमन और मिली राष्ट्रपति अन्वर सादत द्वारा उन्हें स्थायी आवास का आश्वासन ।
- 30 अमेरिका और तुर्की द्वारा नई प्रतिरक्षा सन्धि पर हस्ताक्षर ।

अप्रैल, 1980

- 5 अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के रहने पर सोवियत सभ और अफगानिस्तान के नेताओं में एक समझौते पर हस्ताक्षर ।
- 18 जिवाव्हे स्वाधीन और देश भर में समारोह ।
सोवियत सभ द्वारा जिवाव्हे को राजनयिक मान्यता प्रदान ।
- 25 दो हेलिकॉप्टरों के ईरान में टकरा जाने से बन्धकों को छुड़ाने का अमेरिकी प्रयास विफल ।
सोवियत सभ द्वारा परमाणु परीक्षण ।

- 28 काटंर की बन्धकों को छुड़ाने सम्बन्धी कार्यवाही के विरोध में विदेश मन्त्री साइरस बैस का इस्तीफा, नेपाल द्वारा फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान ।

मई, 1980

- 1 फिलिस्तीनियों के अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा सुरक्षा-परिषद् में निषेधाज्ञा का प्रयोग ।
- 4 यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल जोसेफ ब्रोज टोटो का देहान्त ।
- 9 चीन द्वारा प्रशान्त में अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण की घोषणा ।
- 15 मिजातोविच यूगोस्लाविया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित ।
- 16 जापान की सासायोशी ओहिरा सरकार का पतन और जून में संसद के नए चुनाव का एतान ।
चीन को विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त ।
- 18 यूरोपीय साभा-वाजार द्वारा 22 मई से ईरान के विरुद्ध व्यापारिक नाकेबन्दी का एतान । चीन द्वारा अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का मध्य प्रशान्त में परीक्षण ।
- 22 गुस्ताव हुसाक सर्व सम्मति से चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति निर्वाचित ।
- 28 यांतिजक शामीर इजरायल के नए प्रतिरक्षा मन्त्री ।
- 30 पाकिस्तान द्वारा 20 अरब रुपये के हथियार खरीदने का फैसला ।

जून, 1980

- 7 चीन और सोवियत संघ में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर ।
- 12 जापान के प्रधानमन्त्री मासायाओ ओहिरा का टोकियो में देहान्त ।
- 15 अयातुल्ला खुमैनी द्वारा सांस्कृतिक क्रान्ति की घोषणा ।
- 19 अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा तारापुर परमाणु सयंत्र के लिए यूरेनियम देने का आदेश ।
- 21 चीन सरकार द्वारा भारत-चीन सीमा में वर्तमान नियन्त्रण रेखा को बनाए रखने का मुक्ताव ।
- 24 जापान के चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की भारी जीत ।
- 26 पाकिस्तान के प्रतिरक्षा बजट में 53 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी ।

जुलाई, 1980

- 1 सुरक्षा-परिषद् द्वारा इजरायल के अरब अधिभूत क्षेत्र खाली करने का आदेश ।
- 7 ईरान-ईराक की सीमा पर संघर्ष ।
- 10 टोकियो में अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर और चीन के प्रधानमन्त्री हुया-बुओ-फेङ में पहली बार वार्ता ।
- 11 जापान के नए प्रधानमन्त्री जैको मुजुकी के मंत्रिमण्डल में बर्द नए चेहरे ।
- 26 नेवादा में अमेरिका द्वारा एक परमाणु परीक्षण ।
- 27 ईरान के अषदस्य शाह मुहम्मद रजा पहलवी का काहिरा में देहान्त ।

अगस्त, १९८०

- ६ राष्ट्रपति कार्टर द्वारा नयी परमाणु समरनीति का अनुमोदन ।
- १५ अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी में माधुनिक प्रशेपास्त्र के विकास पर सहमति ।
- २५ ईरान के अपदस्थ शाह के पुत्र राजकुमार रेजा द्वारा निर्वासित सरकार गठित करने की घोषणा ।

सितम्बर, १९८०

- ३ मिस्र और दजरायल में पुनः वार्ता पर सहमति ।
- ४ राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा राष्ट्रकुल देशों के दूसरे एशियाई और प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में विज्ञान भवन में उद्घाटन ।
- ७ हुआ-कुओ-फेड द्वारा चीन के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र और जाओ जियाङ नए प्रधानमंत्री बने ।
- ८ भारत में राष्ट्रकुल के क्षेत्रीय सम्मेलन की समाप्ति पर सयुक्त विज्ञप्ति जारी ।
- १२ तुर्की में रक्तहीन क्रान्ति से प्रधानमंत्री मुलेमान दमरियल सत्ताच्युत और जनरल केनान एवरेन सत्तारूढ़ ।
- २९ ईरान द्वारा युद्ध-विराम का प्रस्ताव अस्वीकार ।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक ४० देशों के इस्लामी शान्ति-सम्मेलन में भाग लेने बगदाद पहुँचे ।

अक्तूबर, १९८०

- ३ फारस की खाड़ी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और आस्ट्रेलिया के युद्धपोतों के जमाव का भारत द्वारा विरोध ।
- ५ अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ते सम्बन्धों की चीन द्वारा आलोचना ।
- १२ राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी सोवियत संघ और बुल्गारिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे ।
- २३ बीमारी के कारण सोवियत संघ के प्रधानमंत्री श्री अलेक्सी कोसीगिन का पद से त्यागपत्र । श्री निखोरोव नए प्रधानमंत्री बने ।
- २८ ईराक और ईरान में मध्यस्थता के लिए भारत सहित ६ निर्णुत देशों की समिति का गठन ।

नवम्बर, १९८०

- २ ईरानी मजलिस (संसद) द्वारा अमेरिकी बन्धकों को रिहा करने की शर्तों का अनुमोदन ।
- ५ रिपब्लिकन पार्टी के रोनाल्ड रीगन अमेरिका के ४०वें राष्ट्रपति निर्वाचित ।
- ७ पश्चिम जर्मनी में चांसलर हेन्सूट बिमरुड के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल द्वारा शपथ ग्रहण ।
- १० माइकल फूट ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नये-नये नेता निर्वाचित ।
- ११ अमेरिका द्वारा बन्धकों की रिहाई के बारे में ईरानी शर्तों का उत्तर अल्जीरिया के माध्यम से प्रस्तुत ।

- 12 ईरान और ईराक में लड़ाई समाप्त करने के लिए संयुक्तराष्ट्र महासचिव डॉ. कुतुबुद्दीन वाहदाईम द्वारा स्वीडन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे को मध्यस्थ नियुक्त करना ।
- 13 माद्रीद में 35 देशों के यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप की तीव्र आलोचना ।
- 20 संयुक्तराष्ट्र महासभा द्वारा सोवियत संघ से अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित ।
- 22 माद्रीद में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन में मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा सोवियत संघ पर प्रहार ।

दिसम्बर, 1980

- 10 पोलैण्ड में सोवियत संघ के हस्तक्षेप करने पर नैटो द्वारा उचित कार्यवाही करने की धमकी ।
- 11 सोवियत राष्ट्रपति लिबोर्निद् ब्रेझ्नेव की भारत यात्रा की समाप्ति के बाद संयुक्त विज्ञप्ति जारी ।
- 17 बाली के सम्मेलन में ओपेक देशों द्वारा भारत को सहायता का आश्वासन । रीगन द्वारा अलेक्जेंडर हेग विदेशमन्त्री नियुक्त ।
- 19 सोवियत संघ के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अलेक्सी कोसीगन का मास्को में देहान्त ।
- 20 मार्क्सवादी प्रणाली पर आधारित धीयतनाम द्वारा नया संविधान लागू ।
- 26 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात द्वारा अफगान छापामारों को अधिक हथियार देने का वायदा ।
- 27 मिस्री राष्ट्रपति सादात द्वारा निर्वासित अफगान सरकार के गठन का आह्वान
- 31 यूनान यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल ।

जनवरी, 1981

- 6 चीन और अमेरिका में सीधी हवाई सेवा शुरू ।
- 7 अमेरिकी बन्धकों के प्रश्न पर ईरान द्वारा अल्जीरिया की मध्यस्थता स्वीकार ।
- 14 चीन द्वारा विश्व बैंक से भारी ऋण की मांग ।
- 18 बंगलादेश द्वारा गंगा-ब्रह्मपुत्र के बारे में भारत का प्रस्ताव अस्वीकार । पाकिस्तान को अनुबन्ध बनाने के लिए सऊदी अरब द्वारा 80 करोड़ डॉलर देने का निश्चय ।
- 20 ईरान द्वारा 52 अमेरिकी बन्धक रिहा । अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रीनाल्ड रीगन द्वारा वाशिंगटन में अपने पद की शपथ ग्रहण ।
- 26 तैफ (सऊदी अरब) में इस्लामी विदेशमन्त्रियों के सम्मेलन में इस्लामी विकास निधि के गठन का निश्चय ।
- 28 तैफ में इस्लामी विदेशमन्त्रियों का सम्मेलन समाप्त ।

फरवरी, 1981

- 1 सोवियत संघ के एक पत्र द्वारा पाकिस्तान में बाइहू चीनी सैनिक मरुते बताया ।
- 6 अफगानिस्तान को राष्ट्रतप की मध्यस्थता स्वीकार, ।
- 9 गुट-निरपेक्ष देशों का नयी दिल्ली में सम्मेलन आरम्भ । उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा विघटन के खतरे के प्रति सदस्य देशों को चेतावनी ।
- 21 अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बबरक कारमाल द्वारा अमेरिकी पड़ोशों के कारण सोवियत सैनिकों का अपने देश में प्रवेश को आवश्यक बताया ।
सोवियत राध द्वारा यूरोप के विभिन्न नगरों को निशाना बनाकर 150 एम एस. 20 प्रक्षेपास्त्रों की स्थापना करना ।
- 22 फ्रांस द्वारा नये परमाणु प्रक्षेपास्त्र का विकास ।
- 23 सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेझ्नेव द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की 26 वीं कांग्रेस में विश्व तनाव कम करने के लिए 8 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत ।

मार्च, 1981

- 4 पश्चिम जर्मनी के राष्ट्रपति कार्ल कार्सटेंस का दिल्ली पहुँचने पर भव्य स्वागत ।
- 10 राष्ट्रपति बनने के बाद रीगन की पहली विदेश यात्रा कनाडा से शुरू ।
- 14 स्विटजरलैण्ड द्वारा संयुक्तराष्ट्र का पुनः सदस्य बनने का फैसला ।
- 19 अमेरिका के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर हेग द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर लगाये गए प्रतिबन्ध हटाये जाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध ।
- 20 ब्रूसेल्स स्थित नटो के देशों द्वारा सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेझ्नेव द्वारा 'वेता' प्रस्तावों को अस्वीकार करने का सुझाव ।
- 24 अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की 50 करोड़ डॉलर के अस्त्र तथा अन्य सहायता का प्रस्ताव

अप्रैल, 1981

- 1 थाईलैंड में सैनिक आन्ति और दो व्यक्तियों द्वारा सत्ता पर अधिकार का दावा ।
- 4 हुआ कुशी फेड के स्थान पर हू यात्रोवाड. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नये अध्यक्ष ।
- 8 अफगानिस्तान में और सैनिकों का आगमन ।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष तेङ्ग मिथाओ पिङ द्वारा भारत को 'बड़ा भाई' बताया । गुट-निरपेक्ष देशों की शान्ति टोली का वगदाद आगमन ।
- 9 पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा लोकसभा में चिन्ता व्यक्त ।
- 13 फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे द्वारा अमेरिका की पश्चिमेशिया की नीति को उग्र बताया ।

- 15 ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री श्रीमती मारग्रेट थेचर के दिल्ली पहुँचने पर भव्य स्वागत ।
- 21 संयुक्तराष्ट्र द्वारा एक नया विश्व बैंक स्थापित करने का निश्चय ।
ईराक द्वारा पाँच छोटे ईरान गठन करने का सुझाव ।
- 22 अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को ढाई अरब डॉलर के अस्त्र देने का आश्वासन ।
- 29 दक्षिण अफ्रीका द्वारा परमाणु ईंधन का उत्पादन ।
सीरिया के सैन्य प्रक्षेपास्त्रों का लेबनान में मिलना ।

मई, 1981

- 1 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध व्यापक प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की निषेधाज्ञा ।
नेवादा के पास अमेरिका का परमाणु परीक्षण ।
- 10 फ्रास्वा मितेरॉ फ्रांस के नये राष्ट्रपति निर्वाचित ।
- 12 पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी सहायता का नया प्रस्ताव स्वीकार ।
- 13 तेरह दिन की विदेश यात्रा के बाद प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का दिल्ली आगमन ।
- 14 अपने हित की रक्षा के लिए समय पड़ने पर नैटो द्वारा बल प्रयोग का निश्चय ।
बंगलादेश में पिछले तीनों वर्ष में 23,400 राजनैतिक हत्याएँ ।
- 16 ग्रेकर द्वारा युगोस्लाविया के नये राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण ।
- 20 ईरान-ईराक युद्ध का फैलाव ।
- 22 भारत और जिम्बाब्वे में व्यापार और तकनीकी सहयोग के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर ।
- 23 एक सर्वेक्षण के अनुसार नवमूर द्वीप को बंगलादेश का नहीं, भारत का भाग बताया जाना ।
- 30 बंगलादेश के राष्ट्रपति जनरल जियाउर्रहमान की चटगाँव में हत्या और उपराष्ट्रपति अब्दुसस्तार कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त ।

जून, 1981

- 4 काठमाण्डो में चीनी प्रधानमन्त्री चाओ च्याङ. द्वारा नेपाल की शान्ति क्षेत्र योजना का अनुमोदन ।
- 8 इजरायल द्वारा ईराक का परमाणु रिएक्टर नष्ट ।
- 10 इजरायल के प्रधानमन्त्री मेनाहिन बेगिन द्वारा अरबों को परमाणु वम न बनाने देने का निश्चय ।
- 13 संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद् में ईराक द्वारा इजरायल के उनके परमाणु सयन्त्र नष्ट करने के कार्य को हमला बताया ।
- 14 ईरानी राष्ट्रपति बनीसदर के देश से पलायन के समाचार ।
- 16 अमेरिका द्वारा चीन को अस्त्र बेचने का निर्णय ।

- 18 इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाहिम बेगिन द्वारा सीरिया पर प्रक्षेपास्त्रों से हमला करने की धमकी ।
- 20 दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया से एकीकरण वार्ता शुरू करने का आग्रह ।
- 22 वनीसदर ईरानी राष्ट्रपति पद से वंचित ।
- 26 दिल्ली पहुँचने पर चीन के विदेशमंत्री हुयाङ्ग हुया का भव्य स्वागत ।
सिनाइ प्रायद्वीप के लिए अमेरिका, मिस्र और इजरायल की 2000 सदस्यीय शान्ति सेना के गठन पर सहमति ।
- 29 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हुयाङ्ग-कुओ-फेङ का अपने पद से स्तीफा और हुयाओबाङ्ग नये अध्यक्ष निर्वाचित ।
ईराक का युद्ध-विराम प्रस्ताव ईरान द्वारा अस्वीकार ।
- 30 चीनी विदेशमंत्री हुयाङ्ग-हुया की कोलम्बो में श्रीलंका के नेताओं से परस्पर सम्बन्धों पर वार्ता ।

जुलाई, 1981

- 6 सोवियत विदेशमंत्री ग्रोमिको द्वारा अफगानिस्तान पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रस्ताव को अव्यावहारिक बनाना ।
यूगोस्लाविया की प्रेसम्बली द्वारा राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल एक वर्ष निश्चित ।
- 9 इजरायल के हमला करने पर सीरिया द्वारा सोवियत सघ से सहायता प्राप्त करने का निश्चय ।
मिस्र और ईराक द्वारा एक-दूसरे के राजनयिक निष्कासित ।
- 10 इजरायली विमानों द्वारा तीन फिलिस्तीनी ग्रहों पर बमबारी ।
- 13 इजरायल के प्रधानमंत्री मेनाहिम बेगिन द्वारा फिलिस्तीनियों को स्वायत्तता देने सम्बन्धी वार्ता का आह्वान ।
- 17 इजरायल द्वारा लेबनान स्थित फिलिस्तीनी ठिकानों पर हमले ।
ब्रिटेन द्वारा बेलीज को 21 सितम्बर को स्वाधीनता प्रदान करने का निर्णय ।
- 21 उत्तर और दक्षिण कोरिया द्वारा एकीकरण का फैसला ।
- 24 लेबनान में इजरायली और फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे में युद्ध-विराम ।
चीन द्वारा अफगान-सोवियत सघ की सीमा सन्धि को अर्थव्यवस्था बताना ।
- 25 अफगानिस्तान पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रस्ताव सोवियत सघ को अस्वीकार ।
- 27 युवराज चार्ल्स की शादी में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी लन्दन के लिए रवाना ।
- 29 सन्दन में युवराज चार्ल्स और लेडी डियाना स्पर्स का विवाह धूमधाम और राजकीय ठाटबाट से सम्पन्न ।
- 31 दिल्ली में भारत और अमेरिकी अधिकारियों की तारापुर के लिए परिष्कृत यूरेनियम सम्बन्धी वार्ता विफल ।

अगस्त, 1981

- 2 मुहम्मद अली रजाई द्वारा ईरान के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण ।
- 8 पश्चिमेशिया की समस्या के समाधान के लिए सऊदी अरब के युवराज फाहद का 8 सूत्री प्रस्ताव ।
- 10 नैरोबी में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा ऊर्जा सम्बन्धी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों का आह्वान ।
इजरायल द्वारा सऊदी अरब का शान्ति प्रस्ताव अस्वीकार ।
- 11 अमेरिका के रीगन प्रशासन द्वारा न्यूट्रान बमों को बनाने की इच्छा व्यक्त ।
- 13 विश्व-शान्ति स्थापना के उद्देश्य से अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेझ्नेव से बार्ता का प्रस्ताव ।
- 16 अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शीघ्र एफ-16 विमान देने का निर्णय ।
- 19 भूमध्यसागर की वायु सीमा में अमेरिका द्वारा लीबिया के बमवर्षकों को गिराया जाना ।
- 23 छाडी के 6 देशों द्वारा लीबियाई विमानों को गिराने के लिए अमेरिकी कार्यवाही की निन्दा ।
ब्रिटेन द्वारा आंटिगुआ को 1 नवम्बर को स्वाधीनता प्रदान करने का निर्णय ।
- 30 राष्ट्रपति मोहम्मद अनी रजाई और प्रधानमंत्री बाहोनार की बम विस्फोट में मृत्यु से ईरान शोकाकुल ।

सितम्बर, 1981

- 1 लीबिया, दक्षिण यमन और इथियोपिया द्वारा संयुक्त प्रतिरक्षा सन्धि पर हस्ताक्षर ।
- 3 अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा अपनी 10 दिन की चीन यात्रा की समाप्ति के बाद ताइवान के मुद्दे को डग से सुलझाने पर बल ।
- 8 सोवियत संघ अमेरिका और नैटो देशों के न्यूट्रान बम का मुकाबला करने के लिए तैयार ।
वाशिंगटन में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और इजरायल के प्रधानमंत्री मेनाहिम बेगिन द्वारा सैनिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने पर बल ।
- 10 सोवियत संघ द्वारा न्यूट्रान बम बनाए जाने की सम्भावना ।
- 12 पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र के अफगान घुसपैठ की शिकायत ।
- 14 संयुक्तराष्ट्र महासभा में दक्षिण अफ्रीका के बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्ताव निर्विरोध पारित ।
- 16 ईराक के इस्मत टी किट्टानी संयुक्तराष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित ।
अमेरिका और इजरायल के बीच नये समझौते पर हस्ताक्षर ।
- 17 ढाका में बंगलादेश और अमेरिका में परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग पर समझौता ।
- 20 सोवियत संघ द्वारा अंगोला में अपने सैनिकों की उपस्थिति की स्वीकृति ।

- 21 120 साल की पराधीनता के बाद बेलीज स्वाधीन ।
- 26 बेलीज संयुक्त राष्ट्र का 156वाँ सदस्य स्वीकार ।
- 29 अफगानिस्तान की समस्या का हल ढूँढ़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव डॉ. कुर्त वान्दहीम की आगाशाही और शाह मुहम्मद दोस्त से बातचीत ।
- 30 मेनबोर्न (आस्ट्रिया) में राष्ट्रकुल देशों का शिखर-सम्मेलन शुरू ।

अक्टूबर, 1981

- 1 ईरान के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुलहसन बनीसदर द्वारा पेरिस में निर्वाचित सरकार का गठन ।
- 4 आर्थिक मानकों पर मेनबोर्न शिखर सम्मेलन द्वारा 16-सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा ।
- 6 मिस्र के राष्ट्रपति अगवर सादात की हत्या ।
अमेरिका द्वारा हिन्द महासागर में अस्त्रों को बढ़ाने का विचार ।
- 7 मिस्र की राष्ट्रीय असेम्बली द्वारा उपराष्ट्रपति हुस्नी मुबारक अगवर सादात के उत्तराधिकारी नियुक्त । मेनबोर्न में राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन समाप्त ।
- 14 हुस्नी मुबारक द्वारा मिस्र के नए राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री पद की शपथ ग्रहण ।
- 22 कनकुन (मेक्सिको) 22 देशों का उत्तर-दक्षिण शिखर सम्मेलन शुरू ।
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और चीन के प्रधानमन्त्री चाओ च्याङ्ग की यात्रा ।
- 29 हुनैन ममावी के ईरान के नए प्रधानमन्त्री पद पर मजलिस (समझ) की पुष्टि ।

नवम्बर, 1981

- 1 अमेरिका द्वारा पश्चिमेशिया में शान्ति स्थापना सम्बन्धी सऊदी अरब का शान्ति प्रस्ताव स्वीकार, लेबनान इजरायल का विरोध ।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक कश्मीर की वर्तमान विभाजन रेखा को सीमा मानने के लिए अग्रहण ।
- 6 सोवियत संघ द्वारा अमेरिका पर परमाणु युद्ध की तैयारी का आरोप ।
- 8 मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक द्वारा सऊदी अरब के पश्चिमेशिया के बारे में 8 सूत्री शान्ति स्थापना प्रस्ताव का अनुमोदन ।
- 9 फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चे के नेता यानिर अराफत द्वारा इजरायल के अस्तित्व को मान्यता देने का संकेत ।
- 10 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा भारत को 57 अरब डॉलर के ऋण का अनुमोदन ।
- 16 अमेरिका के ताइवान को हथियार देने पर चीन द्वारा अमेरिका से अपना राजदूत हटा लेने की धमकी ।
बंगलादेश के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति अब्दुल मत्तार द्वारा सेना की भूमिका की व्याख्या ।

- 18 संयुक्त राष्ट्र द्वारा सोवियत संघ को अफगानिस्तान से हटने का अनुरोध ।
- 21 सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेझ्नेव द्वारा अमेरिका से सभी मुद्दों पर संवाद का आग्रह ।
- 23 वान मे ब्रेझ्नेव और पश्चिम जर्मनी के चान्सलर हेल्मट श्मिड्ट के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों पर बातचीत ।
- 25 भारत 1949 का अनाक्रमण समझौता स्वीकार करने पर सहमत ।
- 28 इस्लामाबाद में पाकिस्तान और टर्की में एक प्रतिरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर ।

दिसम्बर, 1981

- 2 अमेरिकी सेनेट द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 विमान देने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन ।
- 3 संयुक्त राष्ट्र महासचिव डॉ. कुर्तवाल्दहीम द्वारा चुनाव मैदान से हटने का निर्णय ।
- 10 पीकिंग में भारतीय और चीनी प्रतिनिधि मण्डलों में वार्ता शुरू ।
- 11 सुरक्षा-परिषद् द्वारा पेरू के जावियर पेरेज ब कूलार संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव नियुक्त ।
- 15 इजरायल द्वारा गोलान पहाड़ियों पर विधिवत् कब्जा करने का फैसला ।
- 17 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिषद् द्वारा इजरायल के गोलान पहाड़ियों पर कब्जे के फैसले की भर्त्सना ।
- 18 गोलान पहाड़ियों को अपने क्षेत्र में न मिलाने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव इजरायल को अस्वीकार ।
- 24 अमेरिका द्वारा पोलस्का के विरुद्ध व्यापार पर प्रतिबन्ध लागू ।
- 30 अमेरिका द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध ।

जनवरी, 1982

- 2 पेरेज ब कूलार द्वारा संयुक्तराष्ट्र का महासचिव पद ग्रहण ।
- 8 अमेरिका और जापान में पूर्वशिया में संयुक्त प्रतिरक्षा कार्यवाही पर समझौता ।
- 12 अमेरिका द्वारा ताइवान से एफ. एम. समझौता रद्द ।
- 18 अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा रासायनिक अस्त्रों के निर्माण का समर्थन ।
- 20 इजरायली सैनिकों के अग्रेज में तिनाई से हटने पर मिस्र और इजरायल में समझौता ।
- 21 गोलान पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए इजरायल पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा अपनी नियोजना के अधिकार का इस्तेमाल ।

- 24 सीरिया और अल्जीरिया द्वारा विलय का फैसला ।
- 30 संयुक्तराष्ट्र में सीरिया द्वारा इजरायल के विरुद्ध प्रतिबन्धों की मांग ।
- 31 रियाद में फाँस और सऊदी अरब में नौवैयक सुविधाओं सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर ।

फरवरी, 1982

- 1 सीरिया द्वारा पश्चिमेशिया के द्वारे में तीन सूची प्रस्ताव प्रस्तुत ।
- 6 संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिबन्धों सम्बन्धी प्रस्ताव को इजरायल द्वारा अस्वीकृत करना ।
- 9 रीगन द्वारा रासायनिक अस्त्रों के उत्पादन को पुनः शुरू करने का निर्णय ।
- 20 संयुक्त राष्ट्र महासचिव पेरेंज दे कूलार द्वारा ईरान-ईराक में शान्ति की स्थापना की अपील ।
- 25 दक्षिण कोरिया द्वारा एकीकरण की वार्ता का प्रस्ताव ।
- 28 अमेरिका द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबन्ध समाप्त ।

मार्च, 1982

- 9 अफगानिस्तान में एक लाख मोर्चापन सैनिकों की उपस्थिति के समाचार ।
- 10 सिनाइ में मिस्त्री कर्मचारियों का जाना शुरू ।
- 12 अमेरिका के 132 सतत सदस्यों द्वारा परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक का दोनों प्रमुख देशों से आग्रह ।
- 16 सोवियत संघ द्वारा यूरोप में परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर रोक की घोषणा ।
- 17 अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा सोवियत संघ के परमाणु अस्त्रों के रोक के फैसले को निरर्थक बनाना ।
- 24 बंगलादेश में सैनिक शान्ति द्वारा राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार अपदस्थ और ले. जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद द्वारा सत्ता ग्रहण ।
- 29 अमेरिकी प्रशासन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को अस्त्र-शस्त्रों के बिक्री को पुष्टि ।
- 30 ईराक द्वारा युद्ध मोर्चे से अपने सैनिकों को हटाए जाने का आदेश ।

अप्रैल, 1982

- 2 अर्जेंटाइना द्वारा ब्रिटिश बस्तों फाकलैण्ड पर कब्जा ।
- 3 ब्रिटेन द्वारा फाकलैण्ड द्वीप समूह में भारी मात्रा में सैनिक सामग्री भेजना ।
संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा वीटो का प्रयोग ।
- 7 गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा ईरान-ईराक में शान्ति स्थापित करने का प्रयास विफल ।
फाकलैण्ड की समस्या के हल के लिए अमेरिकी विदेश मन्त्री अलेक्जेंडर हेग द्वारा मध्यस्थता का एलान ।

प्रश्नावली

(UNIVERSITY QUESTIONS)

अध्याय—1 (परिचयात्मक)

- 1 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' से आप क्या समझते हैं ? 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' और 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' में भेद प्रस्तुत कीजिए ।

What do you understand by the term 'International Politics'? Distinguish between 'International Politics' and 'International Relations'.

- 2 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की आधुनिक प्रकृति और क्षेत्र के अध्ययन की विवेचना कीजिए ।

Discuss the present nature and scope of the study of International Politics.

- 3 उन तत्वों की व्याख्या कीजिए जो वर्तमान काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप के लिए उत्तरदायी हैं । (1981)

Discuss the factors that are responsible for the changing nature of International Politics in the present era.

- 4 आधुनिक काल में 'विदेश सम्बन्ध' के अध्ययन का महत्व बढ़ने के कारण दीजिए । उसके व्यक्ति-निरपेक्ष अध्ययन के मार्ग में कौनसी कठिनाइयाँ हैं ?

Account for the growing importance of the study of 'International Relations' in Modern times. What are the difficulties in the way of its objective study ?

- 5 "वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का पुनर्गठन हो रहा है जिसमें कि पहले की राज्य व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था धीरे-धीरे नवीन राजनीतिक रूपों में बदलती जा रही है ।" इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए ।

"Contemporary International Relations are going through a reorganization in which the old national state and the old state system are being slowly moulded into new political forms." Elucidate this statement and comment.

- 6 "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्य राजनीतियों की भाँति, शक्ति के लिए संघर्ष है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तिम उद्देश्य चाहे जो भी हो, शक्ति हमेशा तात्कालिक उद्देश्य होता है ।" (मार्गेंथो) उपरोक्त कथन के प्रकाश में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए ।

“International Politics, like all Politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aims of International politics, power is always the immediate aim” (Morgenthau). In the light of the above statement discuss the nature and scope of International Politics.

- 7 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धान्तिक अध्ययन करने से क्या लाभ है? अपने ‘अध्ययन-क्रम’ में प्राधुनिक उभरती प्रवृत्तियों से सम्बन्धित उदाहरण देते हुए उत्तर को स्पष्ट कीजिए।

- 8 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को समझाइए। आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्पोषण से क्या समझते हैं?

Explain International Political System. What do you understand by maintaining the International Political System?

- 9 ‘अन्तर्राष्ट्रीय सौदेबाजी की प्रक्रिया में प्रवृत्तियाँ’ पर एक सक्षिप्त लेख लिखिए। Attempt a brief article on ‘Trends in the International Bargaining Process.’

- 10 “यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था आज भी वही है, जिसमें राज्य इन बात के निर्धारण के लिए एक-दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं कि किमको क्या, कब और कैसे मिला, तथापि वे तरीके बदल गए हैं जिनमें वे एक-दूसरे से प्रतियोगितापूर्ण सौदेबाजी करते हैं और साथ ही बहुत से ऐसे मसले भी बदल गए हैं जिन पर सौदेबाजी की जाती है।” (विलियम कोपलिन) व्याख्या कीजिए।

“The International Political System continues to be a system in which states compete with each-other in order to determine who gets, what, when, and how with only minor influence from International institutions. Even so the ways in which they competitively bargain with each-other and the very issues over which they bargain have changed radically since the classical period” (William D. Coplin.) Elucidate

- 11 “सौदेबाजी के क्षेत्रीय विभाजन की प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के सार्वभौमिकरण का एक स्वाभाविक परिणाम या विकास है।” (विलियम डी कोपलिन) व्याख्या कीजिए।

“Trend towards regional fragmentation of bargaining is a natural outgrowth of the universalization of the International Political System” Explain.

- 12 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वतन्त्र एवं पृथक् अनुशासन मानने के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोणों की समीक्षा कीजिए। (1981)

Examine various views regarding International Politics as a separate and independent discipline.

- 13 उन कारकों की विवेचना कीजिए, जो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप के लिए उत्तरदायी थे?

Discuss the factors that are responsible for changing pattern of International Politics.

- 14 "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रवाद की समझ अनिवार्य है। वास्तव में हमारे समय की राज्य व्यवस्था का समस्त व्यवहार मुख्यतः राष्ट्रीय आशाओं, राष्ट्रीय भय, राष्ट्रीय आकांक्षाओं तथा राष्ट्रीय टकरावों के आधार पर समझाया जा सकता है।" (शार्प तथा कर्क) समीक्षा कीजिए। (1979)

"For students of International Politics an understanding of nationalism is indispensable. Indeed the total behaviour of State system in our days may largely be explained in terms of national hopes, national fears, national ambitions and national conflicts" (Sharp and Kirk.) Discuss and comment.

अध्याय—2 (सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण)

- 15 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के समझने के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए तथा उनकी सीमाओं को भी समझाइए। (1979)

Discuss the various approaches to the study of International Politics and their limitations.

- 16 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक मार्गों (अथवा उपागमों) की व्याख्या कीजिए। (1976)

Examine the scientific and historical approaches to the study of International Politics.

- 17 "यथार्थवादी सिद्धान्त उन सभी तत्त्वों की उपेक्षा करता है जो उद्देश्यों को प्रभावित या परिभाषित करते हैं" अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्गेंथो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। (1979)

"The Realist theory neglects all the factors that influence or define purpose." Present a critical assessment of Morgenthau's Realist theory of International Politics.

- 18 हंस मार्गेंथो द्वारा प्रतिपादित 'यथार्थवाद के छः सिद्धान्तों' का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (1980)

Critically evaluate the 'Six Principles of Realism' as expounded by Hans Morgenthau.

- 19 "दृष्टिकोण तथा विवरण सम्बन्धी अनेक मतभेद यथार्थवादी सम्प्रदाय के विचारकों में पाए जाते हैं तथापि हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मार्गेंथो के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति सिद्धान्त वा वर्णन रंगभूमि के केन्द्र पर अधिकार किए हुए है।" विवेचना कीजिए। (1981)

"Many differences in point of view and on details exist within the realist school of thought; we must recognise, however, that the Morgenthau's version of power theory of International Politics occupies centre of the state." Discuss.

20. मार्गन्यो के 'राजनीतिक वास्तविकता के छः सिद्धान्त' पर एक आलोचना लिखिए और उन सिद्धान्तों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक कल्पना के क्षेत्र में नए विकास की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। (1978)

Attempt a study of Morgenthau's 'Six Principles of Political Realism' and evaluate these principles in the light of new developments; in the field of International Political Theory.

21. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से सम्बन्धित यथार्थवादी सिद्धान्त के प्रमुख लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। उसे एक 'वैज्ञानिक सिद्धान्त' के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया गया है?

Analyse the essential features of Realist Theory for studying International Political Theory. Why has it not been accepted as a 'Scientific Theory'?

22. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के कुछ सिद्धान्तों को समझाते हुए यह बताइए कि वे कहाँ तक वैध हैं? (1980)

Explain some of the main tenets of the Realist Theory of International Politics, and consider their validity.

23. "यथार्थवादी सिद्धान्त उन सभी तत्वों की उपेक्षा करता है जो साध्यों को प्रभावित या परिभाषित करते हैं।" (स्टेनले हॉफमैन)

प्रो० हान्स जे० मार्गन्यो द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मूलभूत प्रस्थापनाओं की गहरी समीक्षा कीजिए। (1978)

"The Realist Theory neglects all the factors that influence or define purposes." (Stanley Hoffman).

Critically examine the main thesis of Professor Hans J. Morgenthau about Realist Theory of power politics.

24. "यथार्थवादियों द्वारा प्रस्तुत घटारहवीं व उन्नीसवीं शताब्दियों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सही नमूना है।" (स्टेनले एच. हॉफमैन)।

उपरोक्त कथन के सन्दर्भ में मार्गन्यो द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (1977)

"The model of the realists is a highly embellished ideal-type of 18th and 19th Century International Relations." (Stanly H. Hoffman).

Critically examine in the light of the above statement the Realistic Theory as propounded by Hans J. Morgenthau.

25. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन सम्बन्धी 'ज्वरस्थावरक दृष्टिकोण' की विवेचना कीजिए। इसमें काप्लान का जो योगदान रहा है, उसकी विशेष रूप से चर्चा करिए।

Discuss the 'System Approach' of the study of the International Politics with special reference to the contribution made by Morton Kaplan in this field.

26. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 'खेल तथा सौदेबाजी' के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।

Discuss the 'Games and Bargaining Theory' of International Politics.

27 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र-सिद्धान्त की विवेचना कीजिए ।
Discuss the Field Theory of International Politics.

28 अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामान्य विचारधारा की व्याख्या कीजिए ।
Explain The General Theory in International Field.

अध्याय—3 (विज्ञान : पुराने और नए विकास)

29 किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान है ? इस सम्बन्ध में क्विन्सी राइट और मॉर्गेंथौ के जो विचार हैं, उनका उल्लेख कीजिए ।

To what extent is International Politics a science ? Describe the views of Quincy Wright and Morgenthau in this respect.

30 "विज्ञान और परम्परावाद के बीच विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए कौन से तरीके प्रयोग में लाए जाने चाहिए ?" स्पष्ट कीजिए ।

"The central issue in the dispute between science and traditionalism is what methods should be adopted for the study of International Politics." Explain

31 "द्वितीय महायुद्ध के बाद की परिस्थितियों में विश्व राजनीति में नई प्रवृत्तियों के जन्म और विकास के लिए एकदम नया परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया ।" परिप्रेक्ष्य में नयापन क्या था और उसने किन नयी प्रवृत्तियों को जन्म दिया ? (1978)

"The post Second World War situation presented a completely new setting for the rise and growth of new trends in World Politics." What was new in the setting and what were the new trends developing therein ?

32 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में जो नए सिद्धान्तों का विकास हुआ उसका सर्वेक्षण कीजिए । (1980)

Attempt a survey of new developments in the theory of International Politics.

33 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सिद्धान्तों से सम्बन्धित नवीन प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए । (1979)

Discuss the recent trends in the Theory of International Relations

34 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का शास्त्रीय अथवा पुरातन दृष्टिकोण क्या है ? हेडले बुल ने वैज्ञानिक विधि को चुनौती दी है, उसकी समीक्षा कीजिए ।

What is the classical approach of the study of International Politics ? Examine the challenge given to this method by Hadley Bull.

35 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में 'विज्ञान बनाम परम्परावाद' पर एक मक्षिण निबन्ध लिखिए ।

Attempt a short essay on 'Science v/s Traditionalism' in the field of International Politics

अध्याय—4 एवं 5 (राष्ट्रीय शक्ति : अवधारणा, सार एवं तत्व)

36 राष्ट्रीय शक्ति के सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए । इसके मुख्य निर्माण तत्व क्या हैं ? (1980)

Define 'National Power' and discuss the various forms of it

- 37 "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, समस्त राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तिम उद्देश्य जो भी हों, शक्ति सदा ही तात्कालिक उद्देश्य होता है।" (मार्गेन्थो)

इस कथन पर टिप्पणी कीजिए तथा अपना मूल्यांकन बनाइए। (1981)

"Power in a political context means, the power of man over the minds and actions of other man." (Morgenthau) Discuss.

Are the elements of National powers stable in their influence? Account for variations in the influence which these exercise over the power of States.

- 38 राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों की व्याख्या कीजिए तथा भूगोल, तकनीकी, नेतृत्व एवं मनोबल के महत्व को समझाइए।

Discuss the basic elements of national power. What is the importance of Geography, Technology, leadership and morale as determinants of national power?

- 39 वे राष्ट्रीय शक्ति के कौन से तत्व हैं जो किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

What are the various elements of national power which have their impact on the evolution of the foreign policy of a country? Discuss by giving concrete examples.

- 40 'अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शक्ति हमारे प्रतिनिधि उपभोग करते हैं, वह हमारी शक्ति में परिणत हो जाती है। जो विफलता या नैराश्य हम अपने राष्ट्रीय समाज में अनुभव करते हैं, उसकी पूर्ति से राष्ट्र की प्रत्याधिकृत शक्ति भंग हो जाती है।' (मार्गेन्थो)।

राष्ट्रीय शक्ति की धारणा को समझाते हुए उपरोक्त कथन की व्याख्या कीजिए।

"The power our representatives wield on the international scene becomes our own, and the frustration we experience within the national community are compensated for by the vicarious enjoyment of the power of the nation." (Morgenthau).

Explaining the concept of National Power elucidate the above statement.

- 41 "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली में शक्ति एक बहुत ही सामान्य शब्द है। राज्यों को शक्तियाँ कहा जाता है और विश्व शक्तियों, महाशक्तियों, द्वितीय श्रेणी की शक्तियों, दुर्बल शक्तियों आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक समाज के शक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है।" (हेराल्ड एवं स्प्राउट) स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए।

"Power is one of the most common terms—in the vocabulary of International Politics. States are called powers and classified as super powers, world powers, great powers, second rate powers, etc. International Politics has been defined as the study of power in a society." (Herald and Sprout). Elucidate.

- 42 राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषा दीजिए। विज्ञान, तकनीकी एवं नेतृत्व का विशेष उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों के तुलनात्मक महत्व की व्याख्या कीजिए। (1977)

Define National Power. Discuss the relative importance of its various elements with particular reference to science, technology and leadership.

- 43 "राष्ट्रीय शक्ति के मूल्यांकन में, पहली त्रुटि होती है एक राष्ट्र की शक्ति का दूसरे राष्ट्र की शक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित न करना, दूसरी एक समय पर वास्तविक शक्ति का भविष्य में सम्भावित शक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित न करना, तथा तीसरी यह है कि एक ही राष्ट्र में एक शक्ति तत्व का दूसरे शक्ति तत्व के साथ सम्बन्ध स्थापित न करना।" (मार्गेन्थो) स्पष्टीकरण कीजिए। (1978)

In the evaluation of national power "the first error consists in not correlating the power of one nation to the power of other nations, the second consists in not correlating actual power at one time to possible power at some future time, and the third consists in not correlating one power factor to others of the same nation." (Morgenthau) Elucidate.

- 44 यह मानकर कि भारत एक सम्भावित महान् शक्ति है, आप राष्ट्रीय शक्ति के किन दो तत्वों को विकास की दृष्टि से प्राथमिकता देने के लिए चुनेंगे ताकि यह सम्भावना कि भारत एक महान् शक्ति के रूप में ढल जाए, इस शताब्दी के अन्त तक चरितार्थ हो सके। (1978)

Assuming that India is potentially a Great Power, which of the two elements of national power you will pick up for priority development in order to realise that potentiality which will render India as a real Great Power before the close of this century.

- 45 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और शक्ति-राजनीति (पावर पोलिटिक्स) को एक समान क्यों माना जाता है? आप किस हद तक इस समीकरण से सहमत हैं? Why is International Politics equated with power Politics? To what extent are you in agreement with this identification?

- 46 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर निम्नलिखित भौगोलिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है—

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (क) स्थिति तथा जलवायु, | (ख) राज्य की स्थिति का तत्व, |
| (ग) भूमि का रूप, | (घ) राज्य का आकार, |
| (ङ) कच्चे माल की उपज, तथा | (च) सीमाएँ। |

Describe the effect on International Politics of the following elements of Geography—

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (a) Location and Climate, | (b) The Factor of Position, |
| (c) Land Form, | (d) Size of the State, |
| (e) Raw Material, and | (f) Boundries, |

- 47 राष्ट्रीय शक्ति के मूल सार एवं तत्वों की विवेचना कीजिए। वर्तमान विश्व में उसकी किंग प्रकार तुलना तथा मूल्यांकन किया जा रहा है? (1981)
Discuss the main essence and elements of National Power. How is it being evaluated and compared in the contemporary world?

अध्याय—6 एवं 7 (राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्व)

- 48 राष्ट्रीय शक्ति में भूगोल की भूमिका पर तकनीकी और विचारधारा का किन प्रकार प्रभाव पड़ता है ? इसकी विवेचना कीजिए । (1981)
Discuss how Technology and Ideology influence the role of Geography on national power "
- 49 राष्ट्रीय शक्ति में भूगोल तथा तकनीकी के तुलनात्मक महत्व का विवेचन कीजिए । रूस, भारत तथा चीन में उदाहरण लेकर अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए । (1979)
Discuss the relative importance of Geography and Technology in national power. Illustrate your answer with examples from the USSR, India and China
- 50 क्या आप इस मत से सहमत हैं कि न तो प्राकृतिक माध्यम ही और न तकनीकी और न कोई और वस्तु अपितु मानव ही एक राष्ट्र की शक्ति में निर्णायक तत्व होता है ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए । (1976)
Do you agree with the view that it is neither natural resources, Technology, nor anything else, but the people who constitute the chief and decisive factor in a nation's power ? Give reasons in support of your answer.
- 51 राष्ट्रीय शक्ति में जनसंख्या अथवा नेतृत्व की भूमिका व महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । (1981)
Critically examine the role and importance of population or leadership in national power
- 52 "राष्ट्रीय शक्ति का जनसंख्या ही सबसे प्रमुख तत्व है ।" समीक्षा कीजिए (1979)
"Population is the single most important element of national power."
Discuss.
- 53 किसी देश की जनसंख्या विश्व राजनीति को किम प्रकार प्रभावित करती है ? अपने उत्तर के पक्ष में विभिन्न राष्ट्रों की जनसंख्या का उदाहरण देते हुए स्पष्टीकरण कीजिए ।
How does the population of state affect International Politics ? Illustrate your answer by suitable examples from the countries of the World.
- 54 "तकनीकी ने शक्ति के स्वरूप तथा राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है ।"
 उपर्युक्त कथन के धारालोक में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तकनीकी की भूमिका व महत्व का विश्लेषण कीजिए । (1980)
"Technology has completely changed the whole complex of power and relations among nations "
Analyse the role and the importance of Technology in the light of the above statement.
- 55 राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं ? आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । राष्ट्रीय शक्ति में प्रविधि और राष्ट्रीय नीतिकता के तत्वों की भूमिका का उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए ।

Critically discuss what you understand by the concept of national power. Examine with illustrations the role of Technology and national morale as elements in national powers.

- 56 'राष्ट्रीय बल' से क्या तात्पर्य है ? राष्ट्रीय बल के तत्व के रूप में विचारधारा का क्या महत्व है ? इसका परीक्षण कीजिए ।

What do you understand by 'National Power'? Examine the significance of Ideology as an element of 'National Power.'

- 57 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका की विवेचना कीजिए । अपने उत्तर का चीन, भारत तथा पाकिस्तान से उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कीजिए । (1978)

Discuss the role of Ideology in International Politics. Illustrate your answer by taking examples from China, India and Pakistan.

- 58 "विचारधारा का महत्व सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिकतम होता है क्योंकि विचारधारा उस पृष्ठभूमि को जिसके सन्दर्भ में निर्माण किया जाता है, निश्चय करती है तथा उस पृष्ठभूमि का अंग होती है ।" (श्लीचर)
इस कथन के सन्दर्भ में, राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर लोकतन्त्रीय तथा साम्यवादी विचारधाराओं के प्रभाव की व्याख्या कीजिए ।

"Ideology is probably most important in International affairs, as it determines and is a part of the setting within which decision-making takes place." (Schleicher).

In the light of the above statement, discuss the effect of democratic and communist ideologies on International behaviour of states

- 59 द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में विचारधारा की भूमिका की विवेचना कीजिए । इस सम्बन्ध में इसकी भूमिका की सीमाएँ भी बताइए ।

Discuss the role which Ideology has played in International Relations since the Second World War. In this connection also indicate the limits of its role.

- 60 शक्ति के अन्तिम स्वरूप जैसे सैनिक शक्ति पर विशेष ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या उपादानों की परीक्षा कीजिए ।

Examine the elements or ingredients of natural power, with particular attention to those factors which make for the ultimate form of power i. e. military power.

- 61 "राष्ट्रीय मनोबल, निश्चय रूप से, कुछ निश्चित और अनिश्चित तत्वों का उल्लेखपूर्ण समन्वय है ।" (पामर एवं पैकिंस) राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्त्व के रूप में मनोबल की विवेचना कीजिए ।

"National morale, we must conclude, is a complex of a few constants and many variables" (Palmer and Perkins). In the light of this statement discuss 'Morale' as an element of National Power.

- 62 'राष्ट्रीय शक्ति का उदय और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।

- 63 'राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा' पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की अवधारणा का प्रभाव बताइए।

अध्याय—8 (राष्ट्रीय हित · अवधारणा और अभिवृद्धि के साधन)

- 64 राष्ट्रीय हित का अर्थ क्या है ? राष्ट्रीय शक्ति के रूप में इसे परिभाषित कीजिए।

What is the meaning of National Interest ? Define it in term of National Power.

- 65 'राष्ट्रीय हित' से आप क्या समझते हैं ? राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के मुख्य साधन क्या हैं ?

What do you understand by the term 'National Interest' ? What are the main Instruments for the promotion of the National Interest ?

- 66 राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में राजनय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (1980)

Examine the role of diplomacy as an Instrument of National Policy.

- 67 "राजनय अब केवल कुलों सामन्तो तथा व्यवसायी सैनिकों के एकाधिकार में नहीं है और न ही राष्ट्रीय राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एकमात्र महत्वपूर्ण अभिनेता है।" (के० जे० होल्मटी)

उपर्युक्त कथन के प्रकाश में 'नए राजनय' के मुख्य आधारों का विवेचन कीजिए। (1979)

"Diplomacy is no longer the monopoly of aristocrats and professional soldiers. Nor, indeed, are nation states the only important actors in International Politics." (K. J. Holsti)

Discuss the basic premises of 'New Diplomacy' in the light of the above statement.

- 68 राजनय के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए और परमाणु युग में इसकी सगति (प्रसंगिकता) का मूल्यांकन कीजिए। (1981)

Discuss the changing nature of Diplomacy and evaluate its Relevance in the nuclear age.

- 69 बीसवीं शताब्दी में राजनय के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। (1981)

Mention the factors responsible for the decline of Diplomacy in the Twentieth Century.

- 70 पुरातन राजनय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्या अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है ? (1979)

Discuss the Chief Characteristics of Old Diplomacy. Do you think it has outlived its utility today ?

- 71 'राष्ट्रीय हित' शब्द की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन के रूप में राजनय की प्रकृति, क्षेत्र तथा सीमाओं की विवेचना कीजिए। (1981)

Explain the term 'National Interest'. Discuss the nature, scope and limits of Diplomacy as an Instrument for promotion of National Interest.

- 72 'कूटनीति' से क्या समझते हैं ? कूटनीति और विदेश नीति में क्या अन्तर है ? कूटनीति के मुख्य कार्यों को समझाइए ।

What do you understand by the term 'Diplomacy'? What is the difference between Foreign policy and Diplomacy? Also describe the functions of Diplomacy.

- 73 साधन के विचार में राष्ट्रीय हित की वृद्धि के तीन-तीन से साधन मात्र मन्त्र महत्वपूर्ण हैं और क्यों ? कूटनीति का महत्व राष्ट्रीय हित के साधन में रूप में बताइए ।

Which Instruments for the promotion of the National Interests of states have, in your view, become the most significant to-day and why? Assign the importance of Diplomacy as an instrument for the promotion of the National Interest.

- 74 राजनय का राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में विवेचना कीजिए । राजनय और विदेश नीति में क्या अन्तर है ?

Discuss Diplomacy as an Instrument of National Power. How is Diplomacy different from Foreign Policy?

- 75 'राजनय' की परिभाषा कीजिए और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाए रखने की दिशा में उसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए । क्या आधुनिक काल में उसका महत्व कम हो गया है ? क्यों ?

Define 'Diplomacy' and evaluate its contribution towards maintaining International Peace. Has its significance decreased in modern times? Why?

- 76 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन में राजनय के कार्यभाग को निर्दिष्ट कीजिए । समीप के गतकाल में राष्ट्रमध्य तथा संयुक्त राष्ट्रमध्य इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होने से इसके कार्यभाग में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है ?

Define the role of Diplomacy in the conduct of International Relations. How far has this role been modified in recent times by the Establishment of International Organisation like the League and the U.N.

- 77 पुरातन अथवा प्रतिष्ठित कूटनीति (राजनय) की तुलना में नवीन अथवा प्रत्यक्ष कूटनीति (राजनय) की क्या परिसीमाएँ हैं ?

What are the limitations of the 'New' or direct Diplomacy as against the old or Classical Diplomacy?

- 78 राजनय को पुराने और नए ऐसे रूपों में बाँटना क्या उचित होगा कि जिनकी अपनी अलग-अलग विशेषताएँ हैं ? विगत तीस वर्षों में भारतीय राजनय का क्या स्वरूप रहा है ?

Is it proper to categorise Diplomacy as old and new, having its distinct features? What has it been like in India during the last thirty years.

- 79 प्रचार तथा राजनीतिक युद्ध की विभिन्न विधियों तथा परिविधियों का परीक्षण कीजिए । द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इनके भाग के महत्व का मूल्यांकन कीजिए ।

- Examine the various methods and techniques of Propaganda and Political Warfare. Assess the importance of their role in International Politics since World War Second.
- 80 राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार और राजनीतिक युद्ध उपकरणों का क्या स्थान है, इसका परीक्षण कीजिए । (1976)
Examine the role of Propaganda and Political Warfare as instruments of National Policy.
- 81 प्रचार की प्रकृति तथा कलापटुता को स्पष्ट करते हुए यह बतलाइए कि यह राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख उपकरण किस प्रकार बन गया है ।
Explaining the nature and the techniques of Propaganda show how War can be an instrument of National Policy.
- 82 राजनीतिक युद्ध एवं प्रचार में अन्तर कीजिए । वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में इनमें से कौनसा साधन उपयुक्त है ?
Differentiate between Propaganda and Political Warfare. Which one of those is a suitable instrument for the promotion of National interests in the present day world ?
- 83 राजनीतिक युद्ध प्रचार से कैसे भिन्न है ? क्या शीतयुद्ध को राजनीतिक युद्ध का एक दृष्टान्त कहा जा सकता है ?
How Political Warfare is different from 'Propaganda'? Can we term the Cold War as a form of Political Warfare ?
- 84 राष्ट्रीय नीति को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में राजनीतिक युद्ध और प्रचार की भूमिका की सोदाहरण व्याख्या कीजिए । (1977)
Discuss with illustrations the role of Political Warfare and Propaganda as an instruments of promoting National Policy.
- 85 आप इस दृष्टिकोण से वहाँ तक सहमत हैं कि वर्तमान समय में, राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने में प्रचार तथा राजनीतिक युद्ध की अपेक्षा आर्थिक साधन अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुए हैं ? अपना उत्तर उचित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए । (1981)
How far do you subscribe to the view that in modern times economic instruments for the advancement of National Interest have proved more effective than Propaganda and Political Warfare ? Illustrate your answer with suitable examples.
- 86 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष के समाधान में राजनय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सोदाहरण व्याख्या कीजिए । (1976)
Bring out with illustrations the role of Diplomacy and International Law in conflict resolution on the International Place.
- 87 "राष्ट्रीय हित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार है ।" स्पष्ट कीजिए ।
"National Interest is the keynote of International Politics." Elucidate.
- अध्याय—9 (राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन—साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं युद्ध)
- 88 उन तरीकों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा बड़ी ताकतें अपने राष्ट्रीय हितों के सम्पादन में आर्थिक तंत्रों का उपयोग करती हैं । सोदाहरण समझाइए ।
Describe the ways in which the big powers use their economic instruments to serve their national interests. Give some instances.

- 89 आर्थिक उपकरणों से आपका क्या तात्पर्य है ? अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए अरब राज्य तेल को एक उपकरण के रूप में कहाँ तक प्रयोग कर रहे हैं ? (1976)
What do you understand by 'economic instruments' ? How far are the Arab Countries using 'Oil' as an instrument for the promotion of their national interest ?
- 90 राष्ट्रीय हित बढ़ान में आर्थिक उपकरणों का क्या स्थान है ? (1978)
What is the role of economic instruments in the promotion of National Interest ?
- 91 आर्थिक उपकरणों से आपका क्या तात्पर्य है ? राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए तथाकथित 'विदेशी आर्थिक सहायता' की भूमिका का विवेचन करिए । (1976)
What do you understand by 'economic instruments' ? Discuss the role of the so-called 'Foreign economic aid' for the promotion of national interest.
- 92 अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति के क्या ध्येय हैं ? इनको प्राप्त करने के क्या विभिन्न उपाय हैं ?
What are the objective of International economic policy ? What are the different devices of realising them ?
- 93 राष्ट्रीय नीति में आर्थिक शस्त्रों से आप क्या समझते हैं ? आर्थिक शस्त्र एवं युद्ध के आर्थिक शस्त्र में अन्तर कीजिए ।
What do you understand by economic instruments of National Policy ? Distinguish between economic weapons and weapons of economic warfare.
- 94 "जब तक साम्राज्यवाद जीवित है, युद्ध अनिवार्य है ।" (लेनिन)
"मानव मन में ही चूँकि युद्धों का जन्म होता है, अतएव मानव मन में शान्ति की रक्षा-व्यवस्था निमित्त की जाए।" (आर्चिबाल्ड मैक्लीश)
उपर्युक्त दोनों कथनों में, युद्ध के 'अर्थ' के सम्बन्ध में कौनसी व्याख्या आपको उचित जान पड़ती है ? (1978)
"So long as Imperialism lives, Wars are inevitable," (Lenin)
"Since it is in the minds of men that wars begin, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed." (Archibald Macleish).
Which of the above two statements is correct in your view as far as the origins of War are concerned ?
- 95 नव उपनिवेशवाद, नव-साम्राज्यवाद और सामाजिक साम्राज्यवाद के अर्थ और प्रकृति की व्याख्या कीजिए । (1976)
Discuss the meaning and nature of neo-colonialism, neo-imperialism and social imperialism.
- 96 साम्राज्यवाद के विरुद्ध मध्य में तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने की दिशा में भारत के योगदान की चर्चा कीजिए । (1977)
Discuss India's contribution in the process of lessening of International tensions and the struggle against Imperialism.

- 97 "यदि साम्राज्यवाद को राज्यों में शक्ति के संघर्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके परिणामों का निर्णय इसकी शक्ति राजनीति के योगदान के रूप में किया जाना चाहिए।" (शूमां) क्या आप इस विचार की अनुस्यूता को वर्तमान शताब्दी में सिद्ध कर सकते हैं ?

"If Imperialism is viewed as a phase of the struggle for power between States, its result must be judged in terms of its role in 'power politics.'" (Schuman) Can you justify this view as relevant to the present century ?

- 98 "चाहे यह सत्य है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त साम्राज्यवाद अथवा वर्तमान उपयोग के अनुसार उपनिवेशवाद की बड़ी पराजय हुई है, परन्तु अभी वह अतीत की वस्तु बिल्कुल नहीं हुआ है।" (गामर मोर पाकिन्स) इस कथन के प्रकाश में साम्राज्यवाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न उद्देश्यों तथा प्रविधियों की व्याख्या कीजिए।

"Although Imperialism or, in present usage, Colonialism has suffered tremendous reverse since World War II, it is by no means a thing of the past" (Palmer and Perkins).

In the light of the above statement, discuss the various motives and techniques of Imperialism in International Politics.

- 99 आधुनिक युद्ध के आर्थिक पहलू का उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर में प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धों का उदाहरण दीजिए। विश्व के पुनर्निर्माण में आर्थिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या योगदान है ?

Describe the economic aspects of Modern War. Illustrate your answer with reference to the World War I and II. What is the part of U.S.A. towards Economic Reconstruction ?

- 100 "साम्राज्यवाद में दूसरे देशों को जीतने का प्रयास निहित रहता है, परन्तु दूसरे देशों को जीतने की नीति को ही हम साम्राज्यवाद नहीं कह सकते।" इस कथन की रोशनी में साम्राज्यवाद की परिभाषा लिखिए।

"Imperialism is a policy of conquest but not every policy of conquest is Imperialism." Define Imperialism in the light of this statement.

- 101 "साम्राज्यवाद का अन्त नहीं हुआ है। वह अन्य रूपों में अभी भी जीवित है।" विवेचना कीजिए। (1979)

"Imperialism is not dead. It survives only in other forms." Discuss.

- 102 साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के मध्य अन्तर बताइए। अभी हाल ही में उन्होंने कोन से नए रूप ग्रहण कर लिए हैं ? विश्व राजनीति पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (1981)

Differentiate between Imperialism and Colonialism. What new forms have recently been taken by them ? Evaluate their impact on World Politics.

- 103 "साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धान्तों का विकास तीन विभिन्न सम्प्रदायों में हुआ है, मार्क्सवादी, उदारवादी और वह जिसे उचित ही कहा गया है—साम्राज्यवाद का पिशाच सिद्धान्त।" (हंस मॉर्गन्थो)

मॉर्गन्थो द्वारा बताए गए साम्राज्यवाद के तीन आर्थिक सिद्धान्तों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (1980)

"The economic theories of Imperialism have been developed in three different schools of thought, the Marxian, the Liberal and one that has aptly been called the devil theory of Imperialism." (Hans Morgenthau) Critically examine the three economic theories of Imperialism as stated by Professor Morgenthau.

- 104 "जब तक साम्राज्यवाद जीवित है, युद्ध अनिवार्य है।" (लेनिन) व्याख्या कीजिए। (1981)

"So long as Imperialism lives, Wars are inevitable." (Lenin). Discuss.

- 105 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्राज्यवाद के भूतकालीन और वर्तमान रूपों की परीक्षा कीजिए। (1980)

Examine the past and the present forms of Imperialism in International Politics.

- 106 वर्तमान एशिया व अफ्रीका में बड़ी शक्तियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे नव-उपनिवेशवाद की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? (1981)

What are the specific features of Neo-colonialism as practised by Big Powers in the present-day Asia and Africa?

- 107 "युद्ध राजनीतिक समागम (सम्बन्धों) का केवल एक भंग है, इसलिए किसी भी तरह स्वयं में एक स्वतन्त्र चीज नहीं है। युद्ध साधनों के सम्मिश्रण सहित राजनीतिक समागम की निरन्तरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।" (कार्लवान क्लॉजविट्ज़)

उपरोक्त कथन को स्पष्ट करते हुए युद्ध का राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में परीक्षण कीजिए। (1976)

"War is only a part of political intercourse, therefore by no means an independent thing in itself. War is nothing but a continuation of political intercourse with an admixture of her means."

(Karlvan Clausewitz)

Elaborate the above statement and examine War as an instrument of National Policy.

- 108 क्या यह मानना अभी भी सही है कि राष्ट्रीय हितों की वृद्धि एवं सुरक्षा के लिए युद्ध सबसे अधिक प्रभावपूर्ण साधन है? 'विश्व-राजनीति' के क्षेत्र में उसका पूरी तरह से बहिष्कार करना सम्भव क्यों नहीं है? (1981)

Is it still correct to maintain that War is the most effective instrument to promote and protect National Interests? Why is it not possible to banish it totally from the field of International Politics?

109 क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि परमाणु युग में युद्ध का महत्व एक राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में समाप्त हो गया है? सिद्ध कीजिए। (1980)
Are you inclined to agree with the view that War has ceased to be an instrument of National Policy in the nuclear age? Justify your answer.

110 युद्ध और शान्ति के प्रश्नों पर आज के गैर-पश्चात्य लेखकों और विचारकों की प्रमुख देनों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। (1976)
Briefly survey the main contributions made by non-western writers and thinkers of today on problems of War and Peace.

111 "एक समुदाय, समस्त राष्ट्र और विशेषकर सम्य राष्ट्रों द्वारा युद्ध सदैव ही राजनैतिक उद्देश्य के लिए और राजनीतिक स्थिति में किए जाते हैं.....युद्ध अन्य साधनों द्वारा राष्ट्रीय नीतियों की निरन्तरता गाव ही है।"
(कार्लवान क्लाउजविट्ज)

उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए और राष्ट्रीय नीतियों और उन्हें त्रियान्वित करने के साधनों के रूप में युद्ध और उनके बीच सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए। (1976)

"The War of a community, of entire nations, and particularly civilized nations, is always called forth by a political motive in a political situation. War is only a continuation of State policy by other means."

(Karlvan Clausewitz).

Comment on the above statement and highlight the relationship between national policies and war as an instrument for their implementation.

112 राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन देने के लिए एक यन्त्र के रूप में सैनिक सहायता के स्वाम की विवेचना कीजिए।

Discuss the role of Military assistance as an instrument for the promotion of National Interest.

113 युद्ध के प्रमुख तथा सधु कार्यों की विवेचना करते हुए यह बतलाइए कि युद्ध राष्ट्रीय नीति का उपकरण किस प्रकार हो सकता है?

Discuss the major and minor functions of War. Show how War can be an instrument of National Policy?

114 युद्ध की परिभाषा कीजिए। युद्ध के विभिन्न प्रकार क्या हैं? युद्ध के विभिन्न विकल्प क्या हैं?

Define War. What are the various types of War? What are the various alternatives of War?

अध्याय—10 (राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ : शक्ति-सन्तुलन, सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान)

115 राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने के साधनों के रूप में शक्ति-सन्तुलन और सामूहिक सुरक्षा के विचार की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। (1977)

Compare and contrast the concepts of Balance of Power and Collective Security as instruments to limit the National Power.

- 116 शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त की परिभाषा को स्पष्ट करने में जो समस्याएँ हैं उनकी विवेचना करते हुए बताइए कि कहाँ तक वे सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहार को समझने में वैध हैं मूल्यांकन कीजिए।
(1980)

Examine a few of the problems involved in defining the concept of the Balance of Power and assess the degree of the validity of the concept in explaining state behaviour in International Politics.

- 117 शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त और व्यवहार की विवेचना कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि आणविक अवरोध के इस युग में शक्ति-सन्तुलन सम्भव नहीं है ?
(1981)

Discuss Balance of Power in theory as well as in practice. Do you agree with the view that in the age of nuclear deterrence Balance of Power is no longer feasible ?

- 118 उन अनेक तरीकों की समीक्षा कीजिए जिनके सहारे सामान्यतः अपने अनुमूल शक्ति सन्तुलन बनाए रखने की कोशिशें होती हैं।
(1979)

Discuss the various ways which are generally adopted to maintain a favourable balance of power.

- 119 'शक्ति-सन्तुलन एक चपटे ब्लैक-बोर्ड पर सफेद चाक में चक्करो व आयातों की एक भावात्मक श्रेणी नहीं है। यज्ञ उन विभिन्न राष्ट्रों व सुदृढ़ निगम व्यक्तियों के बीच नैतिक सम्बन्ध है जो सुरक्षा, धन, प्रतिष्ठा और अपनी जीवन-पद्धति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए एक दूसरे से टक्कर लेते हैं।' (हर्मन फाइनर) इस कथन की विवेचना कीजिए।

"The 'Balance of Power' is not an abstract series of circles and oblongs in white chalk on flat black-board : it is a moral connection between diverse nations, though corporate personalities, that jostle each other for security, wealth, prestige and preservation and expansion of their respective ways of life." (Herman Finer) Discuss the statement.

- 120 "समस्त शक्ति के अनुमानों की यह अनिश्चिता शक्ति के सन्तुलन की व्यावहारिक प्रयोग के अयोग्य हो नहीं बना देती, बल्कि व्यवहार में ये इसको नकारात्मक भी बना देती है।" (मार्गेन्थो) इस वक्तव्य का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

- 121 'शक्ति-सन्तुलन' की परम्परागत अवधारणा की विवेचना कीजिए। वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में परम्परागत शक्ति-सन्तुलन कहाँ तक व्यावहारिक है ?
(1976)

Discuss the traditional concept of 'Balance of Power.' How far is the traditional 'Balance of Power' feasible under the present changed circumstances ?

- 122 "शक्ति-सन्तुलन" के सम्बन्ध में यह परेशानी नहीं है कि इसका कोई अर्थ नहीं है बल्कि परेशानी यह है कि इसके अनेक अर्थ लगाए गए हैं।" (इनिस क्लाउड जून.) इन अनेक अर्थों का उल्लेख कीजिए जिसका क्लाउड ने जिक्र किया है। (1978)
- "The trouble with the 'Balance of Power' is not that it has no meaning but that it has too many meanings" (Innis Claude Jr.). Describe the different meanings that this term has come to acquire as Innis Claude suggests.
- 123 'शक्ति-सन्तुलन' का अर्थ क्या अर्थ लगाते हैं? इनिस क्लाउड जूनियर ने इस अवधारणा के विरोध में जो तर्क दिए हैं, उनका संक्षेप में उल्लेख कीजिए। (1976)
- What do you mean 'Balance of Power'? Summarise the main arguments of Innis Claude Jr. against this concept.
- 124 'शक्ति-सन्तुलन' के विचार से आप क्या समझते हैं? वर्तमान विश्व परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाए रखने में शक्ति-सन्तुलन के औचित्य की व्याख्या कीजिए। (1976)
- What do you understand by the concept of 'Balance of Power'? Discuss its relevance in the context of maintenance of International Peace in the present-day world situation.
- 125 "शक्ति-सन्तुलन का सिद्धान्त प्रथम अर्थ का दावा करता है, परन्तु दूसरे के लिए अयत्नशील रहता है।" टिप्पणी कीजिए।
- "The 'Balance of Power' theory professes the former but pursues the other." Comment.
- 126 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'शक्ति-सन्तुलन' के सिद्धान्त का और उसके महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप प्रोफेसर आर्गेंसकी के इस विचार में सहमत हैं कि 'शक्ति-सन्तुलन' का सिद्धान्त पुराना पड़ चुका है और इसका आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की वास्तविकताओं से मेल नहीं बैठता? (1978)
- Critically examine the concept and importance of 'Balance of Power' in International Politics Do you agree with Professor Organski that the 'Balance of power' concept has become obsolete and does not correspond to the realities of Modern International behaviour?
- 127 "इतिहास की महान् सीढ़ियों पर, शक्ति-सन्तुलन का सिद्धान्त शान्ति स्थापित करने के लिए सदैव सफल रहा है क्योंकि इसने सदैव एक राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली बनने में रोका है, जिससे वह हमारे की शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न न कर दे।" (मार्गेंथौ) क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
- "As a method to maintain International order, the Balance of Power has been eminently successful throughout long stages of history, for it has prevented the rise of any one nation to such power as would have enabled it to destroy the independence of all the other" (Morgenthau) Do you agree with this statement?

- 128 शक्ति-सन्तुलन स्थापित रखने की युक्तियाँ बतलाइए ।
Give the devices for maintaining the 'Balance of Power'.
- 129 कौन से मुख्य कारण हैं जो आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में सामूहिक सुरक्षा पद्धति को एक कारगर शान्ति प्रणाली के रूप में कार्यान्वित करने में बाधा डालते हैं ? कारण सहित विवेचना कीजिए । (1980)
Which are the major reasons whom have prevented the Collective Security from becoming a working peace system in Modern International Relations ? Explain with reason.
- 130 "सामूहिक सुरक्षा-शक्ति के प्रति अयथार्थवादी नहीं है, यह नीति के प्रति अयथार्थवादी है ।" व्याख्या कीजिए । (1980)
"Collective Security is not unrealistic about power; it is unrealistic about policy." Discuss.
- 131 समय-समय पर विकसित की गई 'सामूहिक सुरक्षा' की धारणा की विवेचना कीजिए । उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली बाधाएँ बताइए । (1981)
Discuss the concept of Collective Security as evolved from time to time. Enumerate the difficulties coming in the way to achieve that goal.
- 132 शक्ति-सन्तुलन तथा सामूहिक सुरक्षा के सम्बन्ध की समीक्षा कीजिए । क्या आप इन दोनों को संगत या परस्पर विरोधी समझते हैं ?
Discuss the relationship between 'Balance of Power' and Collective Security. Would you regard the two as compatible or contradictory ?
- 133 "राष्ट्रों के मध्य राजनीति और कुछ नहीं केवल राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों द्वारा सर्वहारा राज्यों के शोषण की राजनीति का ही दूसरा नाम है ।" समीक्षा कीजिए । (1978)
"Politics among Nations is nothing but another name of politics of exploitation of 'Have nots by the Haves' of the family of Nations of our present day world." Comment.
- 134 सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिए । सामूहिक सुरक्षा की अभिवृद्धि में संयुक्त राष्ट्र के योगदान का परीक्षण कीजिए । (1976)
Discuss the concept of 'Collective Security'. Examine the contribution of the United Nations for the promotion of Collective Security.
- 135 आज की दुनियाँ में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के निर्माण में भारत का क्या योगदान रहा है ? (1976)
What has been India's contribution to the building up of a system of Collective Security in the World of today ?
- 136 सामूहिक सुरक्षा तथा शक्ति सन्तुलन के सम्बन्ध की विवेचना संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष सन्दर्भ में कीजिए । (1978)
Discuss the relationship between Collective Security and Balance of Power, with special reference to the United Nations.

- 137 सामूहिक सुरक्षा के माध्यम के रूप में संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार राष्ट्रसंघ का सुधरा हुआ रूप है ? (1977)

In what ways is the United Nations an improvement over the League of Nations as an instrument of Collective Security.

- 138 आपकी दृष्टि में क्या भारत ने एशिया में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान दिया है ? (1976)

Do you think India has made any significant contribution in the building of Collective Security in Asia ?

- 139 "यदि कोई चाहे तो वह गठबन्धनों व सामूहिक सुरक्षा को एक ही समझने की धृष्टता कर सकता है, परन्तु वह ईमानदारी के साथ यह नहीं कह सकता कि वह उसी व्यवस्था की बात करता है जिसे सामूहिक सुरक्षा के नाम के भ्रन्तर्गत, दो विश्व संगठनों ने अपने आदर्श के रूप में स्वीकार किया था।" (इनिस क्लाउड जूनियर) उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए और यह बताते हुए कि किम प्रकार सामूहिक सुरक्षा और गठबन्धनों में कोई समता नहीं है, सामूहिक सुरक्षा की सन्निहित पूर्वधारणाओं की व्याख्या कीजिए। (1977)

"One can identify alliances with Collective Security if he pleases, but if he does; he cannot honestly pretend to be talking about the same kind of system that has been adopted as the ideal of two major world organisations under the name of Collective Security." (Inis Claude, Jr.).
Comment on the above statement, highlighting the underlying assumptions of the concept of Collective Security and also bringing out how the concept is incompatible with alliances.

- 140 एक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक पूर्व परिस्थितियाँ क्या हैं ? समझाइए कि यह तटस्थता तथा शक्ति-सन्तुलन की नीति से किस प्रकार असंगत है।

What are the pre-requisites of an effective system of Collective Security ? Explain how it is incompatible with Neutrality and a Balance of Power policy.

- 141 "विल्सन से लेकर आज तक 'सामूहिक सुरक्षा' के सभी समर्थक इसे 'शक्ति-सन्तुलन' से भिन्नता दिखाते हुए परिभाषित करते रहे हैं। किन्तु अनेक विचारकों ने यह माना है कि 'सामूहिक सुरक्षा' को शक्ति सन्तुलन का एक परिवर्धित संस्करण मानना चाहिए न कि पूरी तरह से भिन्न और 'शक्ति-सन्तुलन' का विकल्प।" आप इन दोनों विचारधाराओं में किसको सही मानते हैं और क्यों ?

"Advocates of 'Collective Security', from Wilson's day to the present, have tended to define and characterise it in sharp contrast to the 'Balance of Power System', whereas other thinkers have said that 'the Collective Security System' should be regarded as simply a revised version of 'The Balance of Power System', not as a drastically different system substituted for the latter." Which of these two views do you support and why ?

- 142 "सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त कहने में जितना सरल है कार्यान्वित करने में उतना ही कठिन।" (सेसिल वी. क्रॉब)। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और समझाइए कि सामूहिक सुरक्षा से सम्बन्धित क्या समस्याएँ हैं ?

"Theory of Collective Security is as simple to state as it is difficult to apply." (Cecil V. Crabb) Comment on this statement and explain the problems connected with Collective Security.

- 143 अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान से आपका क्या तात्पर्य है ? शान्तिपूर्ण समाधान के विभिन्न तरीकों (अथवा विकल्पों) की व्याख्या कीजिए।

(1977)

What do you understand by 'Pacific Settlement of International Disputes'? Discuss various methods (or alternatives) of pacific settlement.

- 144 अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का विशेषकर प्रादेशिक व्यवस्था और समुक्त राष्ट्रसंघ के सन्दर्भ में शान्तिपूर्ण निपटारे की पद्धतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

Explain in detail the methods of the Pacific Settlements of International Disputes with special reference to regional arrangement and the United Nations.

- 145 क्या क्षेत्रीयवाद विश्व-शान्ति को जन्त बना सकता है ? नाटो और सीटो के सन्दर्भ में बताइए।

Can Regionalism promote World Peace? Illustrate with reference to NATO and SEATO

अध्याय—11 (राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ : अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं विश्व सरकार)

- 146 शक्ति सन्तुलन और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए। क्या आप इन दोनों को संगत या परस्पर विरोधी समझते हैं ?

Discuss the relationship between Balance of Power and International Law. Would you regard the two as comparable or contradictory ?

- 147 अन्तर्राष्ट्रीय कानून से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रकृति बताइए। क्या आप समझते हैं कि यह राष्ट्रीय शक्ति पर नियन्त्रण का काम करता है ?

What do you understand by 'International Law'? Describe its nature. Do you think it has some limitations on National Power?

- 148 अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा दीजिए। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? अन्तर्राष्ट्रीय कानून कैसे प्रयुक्त किया जाता है ?

Define 'International Law.' What are its main sources? How International Law is enforced ?

- 149 अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के सघर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का क्या नियन्त्रणकारी प्रभाव पड़ता है? हम दिशा में उसकी शक्ति और सीमाओं का विवेचन कीजिए। (1975)

Discuss the role of, and limitations on, International law as a restraining influence upon the struggle for power on the International scene.

- 150 संकट के समय शान्ति एवं व्यवस्था (भांडर) बनाए रखने के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए बीनयी प्रभावी शक्तियाँ (संस्तर) उपलब्ध हैं? (1981)
Analyse the role of International Law for maintaining Peace and Order in crises times. What effective sections are available for the enforcement of International Law?
- 151 अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा नैतिकता की भूमिका का शक्ति राजनीति पर प्रतिबन्ध के रूप में विवेचना कीजिए। (1980)
Discuss the role of International Law and Morality as checks on power politics
- 152 विश्व सरकार के पक्ष व विपक्ष में दी जाने वाली युक्तियों की विवेचना कीजिए।
Discuss the arguments for and against World Government.
- अध्याय—12 (राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ : निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, विश्व जनमत तथा संयुक्त राष्ट्र सभ)**
- 153 परमाणु युग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने में निःशस्त्रीकरण के उपागम की परीक्षा कीजिए। (1980)
Examine Disarmament as an approach to International Peace in the nuclear age.
- 154 "सामूहिक सुरक्षा के संगठन के बिना निःशस्त्रीकरण सफल नहीं हो सकता।" चर्चा कीजिए।
"Disarmament cannot be successful without the organisation of Collective Security." Discuss
- 155 1945 के उपरान्त निःशस्त्रीकरण से सम्बन्धित समस्याओं की व्याख्या कीजिए।
Discuss the problems connected with Disarmament after 1945
- 156 सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण के पक्ष का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसकी क्या सम्भावनाएँ हैं? (1977)
Critically examine the case for Complete Disarmament. What are its possibilities?
- 157 सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण एवं नियन्त्रित शस्त्रीकरण के विचारों के बीच अन्तर बताइए। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में तुलनात्मक दृष्टि से इनके महत्व की व्याख्या कीजिए। (1976)
Distinguish between the concepts of Complete Disarmament and Controlled Armament. Also discuss their relative importance in promoting International Co-operation.
- 158 निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् किए गए निःशस्त्रीकरण के प्रयत्नों का इतिहास बताइए।
What do you understand by 'Disarmament'? Describe the history of efforts of Disarmament made after the Second World War.

1020 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

- 159 संयुक्त राष्ट्रमंडल द्वारा निश्स्त्रीकरण और हथियारों पर नियंत्रण की समस्याओं को सुलझाने के प्रयासों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।

Critically describe the efforts made by the United Nations in solving the problems of Disarmament and Arms Control

- 160 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।

Assess the contribution of Morality in the field of International Politics.

- 161 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'विश्व लोकमत' की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

Describe the role of 'World Public Opinion' in International Politics.

- 162 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व जनमत के महत्व का परीक्षण कीजिए। 1956 में स्वेज संकट के समय उसने क्या प्रभाव डाला है ? (1977)

Examine the importance of World Public Opinion in the International Politics. How did it influence the crisis of Suez in 1956 ?

अध्याय—13 (वर्तमान विश्व की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ : एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का जागरण, महाशक्तियाँ और तृतीय विश्व)

- 163 युद्धोत्तर काल की उन प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा कीजिए जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। (1979)

Discuss the main characteristics of the Post-War World which brought new trends in International Politics.

- 164 नवीन राष्ट्रों के उदय से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति किस प्रकार प्रभावित हुई है ? (1981)

How the International Politics has been affected by the emergence of the New States ?

- 165 क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि एशिया विश्व राजनीति में अपने आकार, जनसंख्या और सम्भाव्य शक्ति के अनुरूप अधिक सक्रिय भूमिका अदा करेगा ? अपने विचार की पुष्टि में तर्क दीजिए। (1981)

Do you agree with the view that Asia will play a more active role in World Politics, role more commensurate with its size, its population, and its potential might ? Give arguments in support of your view.

- 166 नवोदित एशिया के युद्धोत्तर-विकास किन-किन क्षेत्रों में और कैसे उभरते हुए अफ्रीका से भिन्न लगते हैं ? (1981)

Where and how Post-War developments in resurgent Asia differ from those in rising Africa ?

- 167 "एशिया इस समय विरोधी का मंचार्थ 'कड़ाहा' है और बना रहेगा।" व्याख्या कीजिए। (1980)

"Asia is now, and will continue to be a veritable 'cauldron' of Confrontations." Discuss.

- 168 उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में नए राज्यों का उदय हुआ, तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनका प्रभाव स्पष्ट कीजिए ।

Discuss the circumstances leading to the emergence of New States in Asia the Post-Second World War Period. How did this affect the character of International Politics ?

- 169 "कई महत्वपूर्ण ढंग से एशियाई राष्ट्रीयता पश्चिमी विश्व की राष्ट्रीयता से भिन्न है ।" (पामर और पार्किन्स) स्पष्ट कीजिए ।

"Asian Nationalism has differed from the Nationalism of the Western World in several important respects " (Palmer and Perkins). Elucidate.

- 170 "बड़ी शक्तियाँ एशिया को विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में बाँटने के प्रयत्न में तेजी से जुट रही हैं ।" विवेचना कीजिए । (1978)

"Big Power are furiously making attempts to divide Asia into their respective sphere of influences." Discuss.

- 171 अफ्रो-एशियाईवाद से आप क्या समझते हैं । अफ्रो-एशियाई एकता के इतिहास का वर्णन कीजिए ।

What do you understand by 'Afro-Asian Unity' ? Describe the history of 'Afro-Asian Unity development of the Movement

- 172 समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित करने में उत्तरदायी कार्यों की परीक्षा कीजिए । (1980)

Examine the factors responsible for the Resurgence of Nationalism in contemporary International Affairs.

- 173 'एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के जागरण' पर संक्षेप में निबन्ध लिखिए ।

Write a short critical essay on the 'Resurgence of Asia, Africa and Latin America'.

- 174 विशेष रूप से प्रथम महायुद्ध के बाद, एशिया के कौन से भाग अधिकांशतः तथा क्यों बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व में आए हैं ? उन्हें अब किस सीमा तक वास्तविक रूप से स्वतन्त्र माना जा सकता है ? (1981)

Why and which parts of Asia have been mostly subjected, particularly after World War I, to the domination of Big Powers ? To what extent can they now be regarded as really independent ?

- 175 वर्तमान अफ्रीका में कौनसी राजनैतिक प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं ? विश्व-राजनीति में इतना बड़ा महाद्वीप अपना व्यक्तित्व स्थापित करने में क्यों नहीं सफल हो सका है ? (1981)

What political trends are emerging in Contemporary Africa ? How has this large continent not been able to carve out its own identity in World Politics ?

- 176 अफ्रीकी राजनीति की नवोदित प्रवृत्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या कुछ ऐसी भी विशेषताएँ हैं जिन्हें हम केवल अफ्रीकी समाज की विशेषताएँ कह सकेंगे? (1979)

Summarise the new trends emerging in the African Politics today. Are there any typically African features which we can say the characteristics of African Society only?

- 177 "अफ्रीकी राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन अब केवल उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलन मात्र ही नहीं रह गए हैं बल्कि उन्होंने नई दिशा दी है।" इन राष्ट्रीय आन्दोलनों की नई प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। (1980)

"The African National Liberation movements are not longer simply Anti-colonial Movements but have attained new direct ones as well" What new trends you are witnessing in these Liberations Struggles?

- 178 "हम यह जानते हैं कि विभाजित अफ्रीका, चाहे वह कितने ही जोश के साथ अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा क्यों न करे, बड़ी आसानी के साथ नव-उपनिवेशवाद का शिकार बन जायेगा। कमजोर और विभाजित कभी भी सर्वांगीण स्वतन्त्रता को बनाए रखने की आशा नहीं कर सकते।" (जुलियस न्येरेरे)

उपरोक्त कथन के सन्दर्भ में अफ्रीकन एकता को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नों के महत्त्व की व्याख्या कीजिये। वे अश्वचने क्या है जिन्होंने इन प्रयत्नों को सफल नहीं होने दिया है। (1976)

"We know a balkanized Africa, however loudly it might proclaim to the World its independence, will in fact be an easy prey to the forces of Neo-colonialism. The weak and divided can never hope to maintain a Dignified independence" (Julius Nyerere)

Discuss in the light of the above statement the importance of the efforts made so far to achieve African Unity. What are the bottlenecks in which these efforts get bogged down?

- 179 एशियाई तथा अफ्रीकी पुनर्जागरण ने संयुक्त राष्ट्र को किस प्रकार प्रभावित किया है? (1977)

How has Asian and African Resurgence influenced the United Nations?

- 180 दक्षिण-पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद के नाश के परिणामों की विवेचना कीजिये तथा इस सन्दर्भ में इस प्रदेश में महाशक्तियों की नीतियों की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिये। (1977)

Analyse the consequence of the collapse of Imperialism in South East Asia and discuss in this context the major trends in the policies of Big Powers with regard to this region

- 181 अफ्रीका-एशियाई एकता के पतन के कारण लिखिए।

What led to the erosion of Afro-Asian solidarity?

- 182 मध्यपूर्व की द्वितीय युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।
Write a short essay on International Politics of the Middle East after World War II.
- 183 अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में मध्यपूर्व के तेल ने जो भूमिका प्रदा की है उसकी विवेचना कीजिये।
Discuss the part played by Middle East Oil in International Diplomacy.
- 184 हिन्द महासागर की क्या समस्या है ? इस सम्बन्ध में बड़ी शक्तियों और तटवर्ती राष्ट्रों की भूमिका एवं प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिये। (1976)
What is the problem of the Indian Ocean ? Also discuss the role of Major Powers in its regard and also the reaction of the littoral States.
- 185 'लैटिन अमेरिका' से आप क्या समझते हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'लैटिन अमेरिका' की भूमिका की व्याख्या कीजिये। (1976)
What do you understand by 'Latin America' ? Discuss the role of 'Latin America' in International Politics.
- 186 "ऐसा प्रतीत होता है कि लैटिन अमेरिका के अधिकार में अनेक ऐसी बातें हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उसका महत्त्व बढ़ाने का साधन बन जाती हैं।" (पामर एव पर्किन्स)। विवेचना कीजिये।
"Latin America would seem to possess a number of conditions that tend to increase its importance in International Affairs." (Palmer and Perkins) Comments.
- 187 "कल के दो प्रतिबद्ध शत्रु, जिन परिस्थितियों के वश में एक दूसरे के इतने नजदीक आ रहें हैं कि लगता है कि एक अपवित्र गठबंधन होने ही वाला है ताकि अपनी अफो-एशियाई नीतियों में तालमेल बंठा सकें ? विवेचना कीजिये। (1979)
"What factors have brought the two sworn enemies the United States of America and Communist China so close to each other that they appear to be on the verge of forgoing an Unholy Alliance in regard to their Afro Asian Policies ?" Discuss.
- 188 विशेष रूप से पश्चिमी एशिया अथवा दक्षिणी एशिया के सन्दर्भ में समुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
Describe the main features of the U.S.A.'s foreign policy with special reference to West Asia and South Asia.

अध्याय-14 (भारत और उसके पड़ोसी)

- 189 भारत की विदेश-नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं ? 1947 के बाद से उसके विकास के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिये।
What are the determinants of India's Foreign Policy ? Discuss the salient points of its evolution since 1947.

- 190 भारत-पाक संघर्ष के प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिये । भारत और पाकिस्तान के संघर्ष ने भारतीय विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित किया है?
Explain the major factors responsible for Indo-Pak Conflict. How it has affected the Indian Foreign Policy ?
- 191 भारत-चीन संघर्ष के कारणों का विश्लेषण कीजिये और 1959-62 के बीच भारत के प्रति चीन के रवैये में जो परिवर्तन आया उसका निरूपण कीजिये ।
Analyse the factors in the India-China Conflict and discuss the change in China's attitude towards India during 1959-62.
- 192 1947 से आज तक के भारत-पाक सम्बन्धों की विवेचना कीजिये । क्या 1971 के बाद इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है ?
Discuss the Indo-Pak Relations since 1947 Has there been a major change since 1971?
- 193 पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिये । यह किस सीमा तक उप-महाद्वीप में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाने में सफल रही है ?
Examine the Indian Foreign Policy towards neighbouring countries. How far has it succeeded in fostering peace and goodwill in the sub-continent ?
- 194 भारत-चीन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए पुनर्मेल की सम्भावनाओं का विवेचन कीजिये ।
Analyse the India-China Conflict and discuss the possibilities of reapproachment
- 195 1950 से भारत-चीन सम्बन्धों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये । (1976-77)
Critically examine the Sino-Indian relations since 1950
- अभ्यास—15 (सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश नीति)**
- 196 'सोवियत संघ के उत्थरण' पर समीक्षात्मक निबन्ध लिखिये ।
Write a critical essay on 'The Rise of Soviet Union'.
- 197 स्टालिन की मृत्यु के बाद एशिया के प्रति सोवियत नीति के विकास की विवेचना कीजिये ।
Comment on the development of Soviet Policy towards Asia since the death of Stalin.
- 198 हाल ही में पूर्वी यूरोप में सोवियत नीति को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिये । मई 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप की विवेचना कीजिये ।
Examine the factors which have influenced the Soviet Policy in Eastern Europe in recent years. How do you account for the Soviet Intervention in Czechoslovakia in 1968 ?

- 199 आधुनिक वर्षों में सोवियत रूस की विदेश नीति किन रूपों में परिवर्तित हुई या सुधरी है ? उत्तर की पुष्टि में ठोस उदाहरण दीजिये ।
In what respect has the foreign policy of the U. S. S. R. modified in recent years ? Give concrete instances to illustrate your answer.
- 200 "सोवियत संघ व चीन दोनों ही साम्यवादी शक्तियों के परराष्ट्र नीति विषयक चिन्तन में जापान एक अजेय तत्व बना हुआ है ।" विवेचना कीजिये । (1976)
"Japan remains of the two major communist factor in the foreign policy calculations of the two major communist powers, the Soviet Union and China." Discuss.
- 201 पश्चिम एशिया संबंधी सोवियत नीति के प्रमुख तत्व क्या-क्या हैं ? क्या यह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रही है ? (1980)
What has been the salient features of Soviet Policy in West Asia. Has it failed to achieve its main objectives ?

अध्याय-16 (सं० 110 अमेरिका का उदय और उसकी विदेश नीति)

- 202 'संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्कर्ष' पर संक्षिप्त प्रालोचनात्मक निबन्ध लिखिये ।
Write a short critical essay on 'The Rise of the U. S. A.'
- 203 अमेरिकन विदेश नीति की वर्तमान प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिये । आपकी राय में एशिया के प्रति अमेरिकी नीतियों पर विद्यमान मुद्द का क्या प्रभाव पड़ा है ?
Analyse the modern tendencies of American Foreign Policy. How far the Vietnam War has affected American Policies towards Asia ?
- 204 "पहले एशिया" अथवा 'पहले यूरोप' के सन्दर्भ में पुद्गोत्तर अमेरिकी विदेश नीति में क्या-क्या मुख्य परिवर्तन आए हैं ?—विश्लेषण कीजिये ।
- 205 एशिया के प्रति निक्सन की नीति में आपको क्या कोई परिवर्तन लक्षित हुआ ? अगर हाँ, तो बताइये वे परिवर्तन क्या थे ?
Did you notice any change in Nixon's Asian Policy ? If yes, please explain these changes.
- 206 दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमेरिकी नीति के उद्देश्य क्या हैं और विद्यमान के साथ अमेरिका के संश्लिष्ट होने के बाद इस नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं ?
Examine the aims of the American Policy in South-East Asia. How has the American involvement in Vietnam affected these aims ?
- 207 अमेरिका और भारत के बीच सम्बन्धों का वर्णन कीजिये और बंगलादेश के सम्बन्ध में अपनाई गई अमेरिका की नीति की भी विवेचना कीजिये ।
Describe the relations between U.S.A. and India and also discuss these relations with special references to the context of Bangladesh.
- 208 संयुक्त राज्य अमेरिका और जनवादी चीनी गणराज्य के पारस्परिक सम्बन्धों की नूतन प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परीक्षण कीजिये ।
Examine briefly the recent trends in relations between the United States of America and the People's Republic of China.

- 209 "द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्, अमेरिकी नीति-निर्माता साम्यवाद को मात्र सैनिक चुनौती के रूप में मानते थे। नाटो के निर्माण से उन्होंने यूरोप को निरबुध रूप में ऐसे आक्रमण की सम्भावना के विरुद्ध विभाजित कर दिया था जिसका कोई नियोजन नहीं था।" (जार्ज एफ. केनन)

उपरोक्त कथन के प्रकाश में शीत युद्ध में निहित मान्यताओं की चर्चा कीजिये तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (1977)

"After the Second World War, American policy makers could see communism only in terms of a military threat. In creating NATO they had drawn a line arbitrarily across Europe against an attack no one was planning." (George F Kennan).

Discuss the assumptions underlying the Cold War in the light of the above statement and bring out the main aspects of its impact on International Politics after the Second World War.

- 210 चीन-अमेरिकी समीपीकरण के विभिन्न पक्षों की विवेचना कीजिये तथा उनकी सीमाओं भी समझाइये। (1980)

Discuss the various aspects of Sino-American rapprochement and its limitations?

- 211 विषयनाम युद्ध के बाद चीन-अमेरिकी सम्बन्धों की परीक्षा कीजिये। (1979)
Examine Sino-American relations since the end of the Vietnam War.

- 212 अमेरिका के राष्ट्रपति कार्टर की निगरानी में मिस्र के राष्ट्रपति सादात व इजरायल के बैगिन के बीच जो समझौते हुए ताकि पश्चिम एशिया का संकट हल हो, उस पर अपने विचार प्रकट कीजिये। (1979)

Discuss the agreements reached between Begin of Israel and President Sadat of Egypt under the guidance of President Carter to resolve the West Asian crisis. What are your own views regarding these agreements?

- 213 "तीसरे विश्व के सैनिक शासन साम्राज्यवादी शक्तियों की सबसे अधिक विश्वस्त अनुचार सरकारें सिद्ध हुई हैं।" इस कथन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को पुनः शस्त्र देने से आने वाले खतरों की विवेचना कीजिये।

"Military regimes in the Third World have proved to be most reliable client States of the Imperialist powers" In the light of this statement discuss the implications of re-arming of Pakistan by the U. S. A.

- 214 "युद्धोत्तर परिस्थितियाँ अमेरिका के साम्राज्यवादी दुनिया के मंत्री (बाजी) बनने की महत्वाकांक्षा रखती हैं।" उक्त वक्तव्य के प्रकाश में युद्धोत्तर-काल के प्रथम दो दशकों में अमेरिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (1978)

"Under the Post-war conditions the Imperialists of the U. S. A. aspire to the role of the world gendarme." Assess the role played by America in the light of the above statement during the early two decades of Post-war period.

अध्याय-18 (शीत युद्ध)

- 215 शीत-युद्ध की प्रकृति, प्रारम्भ तथा मुख्य प्रावस्थाओं की व्याख्या कीजिये।
Discuss the nature, origin and main phases of the Cold War.
- 216 शीत-युद्ध और निरपेक्षता के पारस्परिक सम्बन्ध की परीक्षा कीजिये।
Attempt an analysis of the pattern of relationship between the Cold War and Non-alignment.
- 217 तथाकथित 'शीत-युद्ध' के क्या कारण हैं? जिन मुख्य बातों को लेकर यह लड़ा जा रहा है और 1946 से जिन मुख्य घटनाओं के दर्शन इतने किए हैं उनका वर्णन कीजिये।
What are the causes of the so-called 'Cold War'? Indicate main fronts on which it is being fought and the main episodes it has witnessed since 1946.
- 218 "जिसे शीत युद्ध कहा जाता है उसने दोनों ही महती शक्तियों की राष्ट्रीय नीतियों के लक्ष्य की पूर्ति में मदद की।" क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार प्रकट कीजिये। (1979)
"What is called the Cold War served the ends of National Policy of both the Super Powers" Do you agree? Present your views about it.
- 219 शीत युद्ध के उदय और विस्तार के कुछ मुख्य चरणों की विवेचना कीजिये। क्या शीत युद्ध समाप्त हो गया है? कारण सहित उत्तर दीजिये। (1980)
Examine the major phases in the rise and spread of the Cold War. Is the Cold War now over? Support your answer with arguments.
- 220 क्या आप इससे सहमत हैं कि "बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं के कारण विश्व को एक स्थायी नये शीत युद्ध की ठंड में जमना सरल नहीं है।" (जार्ज अर्बातोव) तर्कसहित उत्तर दीजिये। (1981)
Do you agree with the view that "It is not easy to freeze the World in a permanent New Cold War because of changed International Realities" (Georgy Arbatov) Give reasons of your answers.
- 221 शीत-युद्ध के कारण बताइये। क्या यह अभी तक फैल रहा है? तृतीय विश्व के देशों पर शीत युद्ध के प्रभाव का संक्षेप में विश्लेषण कीजिये। (1981)
Account for the causes of Cold War. Is it still continuing? Briefly analyse the impact of Cold War on the countries of Third World.
- 222 शीत-युद्ध की शिथिलता से आपका क्या तात्पर्य है? यूरोप में शान्ति एवं सहयोग की अभिवृद्धि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के प्रयासों की व्याख्या कीजिये। (1976)
What do you understand by 'Thaw in Cold War'? Discuss the efforts made by the U. S. A. and the Soviet Union to promote peace and co-operation in Europe.
- 223 द्वितीय महायुद्धोत्तर युद्ध में शीत-युद्ध के विकास को बताइये।
Trace the growth of the Cold War in the Post World War II Period.

- 224 "शीत-युद्ध से तनाव शंयित्व तक.... इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व की राजनीतिक स्थिति घागे बढ़ी है। शीत-युद्ध और तनाव शंयित्व के बीच अन्तर बताइए और तनाव शंयित्व के लिए जिम्मेदार कारणों की विवेचना कीजिये। (1976)

"From the Cold War to detente...." that is how the world political situation has moved since the Second World War. Distinguish between Cold War and detente and also account for the development of Detente.

अध्याय-18 (पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण और पुनसंगठन)

- 225 जर्मनी के पुनर्एकीकरण की समस्या की विवेचना कीजिये।
Discuss the problem of re-unification of Germany.
- 226 पश्चिम यूरोप में सहयोग के आन्दोलन की व्याख्या कीजिये और यह स्पष्ट कीजिए कि फ्रांस की नीति के कारण उसमें क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं।
Discuss the movement of West-European Co-operation since 1945 and point out the major difficulties arising out of France.
- 227 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् यूरोप का पुनर्वास किस प्रकार किया गया था ? पुनर्वासित यूरोप 1939 के पूर्व यूरोप से किस प्रकार भिन्न है ?
How was Europe rehabilitated after World War Second? How does the rehabilitated Europe differ from the pre-1939?
- 228 'पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण और पुनसंगठन' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।
Write a short essay on 'Re-building and Re-organisation of Western Europe'.
- 229 यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या हैं ? पश्चिमी यूरोप के पुन. निर्माण तथा पुनः व्यवस्था में यूरोपीय आर्थिक समुदाय वहाँ तक योगदान दे रहा है ? (1976)
What are the main political objectives of the European Economic Community? How far is the European Economic Community contributing towards re-building and re-organisation of Western Europe?
- 230 द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के आर्थिक और सैनिक एकीकरण के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिये। (1976)
Discuss the attempts made to Unite West Europe economically and militarily after the Second World War.
- 231 "जैसे ही पश्चिमी यूरोप युद्धोत्तर सन्दर्भ में विश्व राजनीति का केन्द्र नहीं रह गया, इसके अमेरिकी नेतृत्व व देखभाल में पुनर्निर्माण और पुनसंगठन का कार्य अपेक्षाकृत सरल हो गया।" इस कथन की समीक्षा कीजिये। (1978)
"As Western Europe ceased to be the centre of World Politics in Post War setting, the task of its re-building and re-organisation under the over-all supervision and leadership of America became easier." Discuss this statement.

- 232 द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् पश्चिमी यूरोप को एकताबद्ध करने के प्रयासों के राजनैतिक सैनिक तथा आर्थिक पक्षों की विवेचना कीजिये। (1977)
Discuss the politico-military and economic aspects of the efforts to achieve West European Unity after the Second World War.
- 233 "एक पुनर्गठित पश्चिमी यूरोप शांति और प्रगति का कारण बनने के बजाय और कुछ भी कहा जा सकता है।" विवेचना कीजिये। (1980)
"A re-organised Western Europe is proving anything but a factor of peace and progress." Comment.
- 234 यह कैसे हुआ कि जब पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व अपने-अपने देशों की राजनीतिक-सैनिक एवं आर्थिक शक्तियों में, अपने प्रमुख परस्पर-विरोधों को दूर करते हुए, मेल-जोल बैठाने में सफल रहा, जब एशिया में किसी पैमाने पर भी ऐसी एकता घटित नहीं हो पाई ? (1981)
How while Western European Leadership succeeded in welding their countries politico-military and economic forces, ironing and their principal contradictions, the same thing could not take place in Asia on any scale ?
- 235 "यूरोपीय मामलों में महाशक्तियों की भूमिका को यूरो-साम्यवादी आन्दोलन एक अग्रणी दिशा देने की संभावना रखता है।" विवेचना कीजिये। (1979)
"Euro-Communist movement is likely to have some wholesome effect on the role of super-powers in European Affairs." Comment.

अध्याय-19 (आणविक शस्त्रों का प्रभाव)

- 236 परमाणु अस्त्रों के विस्तार से उत्पन्न खतरे की विवेचना कीजिये। इस खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? (1977)
Examine the danger posed by the spread of nuclear weapons. What steps have been taken to face this danger ? Discuss.
- 237 "परमाणु" विश्वसनीयता सर्वत्र विद्यमान है, यह सामरिक चिन्तन, दूटनीति, यहाँ तक कि भविष्य में मानव (अथवा मनुष्य जाति) दशा के विषय में अनुमान सम्बन्धी विचारों को प्रभावित करता है।" (एडमण्ड स्टिलमैन एवं विलियम पफ़)
उपरोक्त बयान के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'परमाणु' की भूमिका की विवेचना कीजिये। (1976)
"The atomic credibility is all-pervasive it affects strategic thinking, diplomacy, and even speculative thought on the future condition of mankind." (Edmund Stillman and William Pfaff).
In the light of the above statement discuss the role of 'Atom' in International Politics.
- 238 विश्व-राजनीति में आणविक शस्त्रों की भूमिका बताइये। उसके और आधिक फैलाव को रोकने के विषय में महा-शक्तियों के द्वारा उठाये गये कदमों का मूल्यांकन कीजिये। (1981)
Discuss the role of Nuclear Weapons in World Politics. Evaluate the steps taken by Super-powers to prevent their further proliferation.

अध्याय-20 (गुट-निरपेक्षता और बदलते प्रतिमान : भारत की गुट-निरपेक्षता)

- 239 'असंलग्नता' से आप क्या समझते हैं ? असंलग्नता की नीति के आधार तथा मुख्य तत्वों को भारत की असंलग्नता नीति के सन्दर्भ में समझाइये ।
What do you understand by the term 'Non-alignment'? Describe the basis and main text of Non-alignment with special reference to India's Non-alignment Policy.
- 240 असंलग्नता की नीति के प्रमुख सिद्धान्तों की परीक्षा कीजिये । वर्तमान में वे कहाँ तक उपयुक्त हैं ? भारत के अनुभव के प्रकाश में विस्तार से विवेचना कीजिये ।
Critically examine the main postulates of the policy of Non-alignment. To what extent are they relevant now ? Discuss in detail by drawing up India's experience.
- 241 असंलग्नता की नीति के विचार तथा प्रयोग में वर्तमान प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिये ।
Examine the present trends in the concept and practice of Non-alignment.
- 242 गुट-निरपेक्षता के बदलते हुए स्वरूप की विवेचना कीजिये । रूस तथा अमेरिका के सुधरते हुए सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह नीति कहाँ तक ठीक है ?
(1978, 1980)
Discuss the changing pattern of the policy of Non-alignment. How far is this policy relevant in the content of Detente between USA and USSR.
- 243 गुट-निरपेक्षता की धारणा का परीक्षण एवं व्याख्या कीजिये । किस देश की विदेश-नीति को गुट-निरपेक्ष मानने के लिए कौन-से मानदण्ड हैं ? वर्तमान विश्व में गुट-निरपेक्षता के कौन-कौन से प्रतिमान पाए जाते हैं ? (1981)
Explain and examine the concept of 'Non-alignment'. What are the criteria to determine a country's foreign policy as Non-aligned ? Are there different patterns of 'Non-alignment' available in the contemporary world ?
- 244 विश्व राजनीति पर गुटनिरपेक्ष (विलग्न) आन्दोलन के प्रभाव की विवेचना कीजिये और यह भी बताइये कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को निरूपित करने में किस प्रकार प्रभावी शक्ति बनाया जा सकता है । (1981)
Discuss the impact of Non-aligned movement on World Politics. Also suggest ways and means to make it an effective force in shaping International Relations.
- 245 भारतीय विदेश नीति के सन्दर्भ में गुट-निरपेक्षता के आधारभूत सिद्धान्तों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये । (1980)
Critically examine the basic postulates of Non-alignment with special reference to the Foreign Policy of India.
- 246 "विलग्नता की नीति ही भारत की समूची परराष्ट्र नीति नहीं है । विलग्नता के क्षेत्र के बाहर ही परराष्ट्र में हो रहे नये विकास पर नजर डाली जा सकती है ।" नये विचारों की विवेचना कीजिये । (1979)

"Non-alignment is not the whole of India's Foreign Policy. It is there in arenas other than those belonging to Non-alignment that one has to look for new developments." Discuss.

- 247 भारतीय विदेश नीति में निरन्तरता और परिवर्तन की व्याख्या कीजिये।
Explain the change and continuity in the Indian Foreign Policy (1981)
- 248 भारत द्वारा ग्रहण की गई असंतन्त्रता (गुट-निरपेक्षता) की नीति से आप क्या समझते हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में असंतन्त्रता की नीति की उपयुक्तता (औचित्य) का परीक्षण करिये। (1976)
What do you understand by the policy of Non-alignment as adopted by India? Examine the validity of Non-alignment under the changing situation in International Politics.
- 249 "भारत की परराष्ट्र नीति के मामले में नेहरू जी के शब्द ही आखिरी शब्द रहेंगे। विचारों की जो दुनिया नेहरू अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ गए, उसमें उनके उत्तराधिकारी कुछ भी 'नया' नहीं जोड़ पाए।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिये।
"The last words on Foreign Policy of India shall remain those of Pandit Nehru. There is nothing New that his successors could claim to have contributed to that store-house of ideas left by Nehru." Do you agree? Give reasons in support of your answer.
- 250 नेहरू के बाद की भारत की परराष्ट्र नीति की विवेचना कीजिये। क्या नेहरू की परराष्ट्र नीति में उनके उत्तराधिकारियों से कुछ भी नया जोड़ा जा सकता है ? (1978)
Discuss Post-Nehru India's Foreign Policy. Has anything new been added to Nehru's Foreign Policy by his successors?
- 251 भारत की गुट-निरपेक्ष नीति के सन्दर्भ में आप भारत-रूस सन्धि (अगस्त 1971) को किस प्रकार उचित ठहरायेंगे ? (1977)
How would you fit in the Indo-Soviet Treaty (August 1971) within the Indian Policy of Non-alignment?

अध्याप-21 (द्वि-ध्रुवीयता और बहुकेन्द्रवाद)

- 252 "द्वि-ध्रुवीयता और बहुकेन्द्रवाद" पर निबन्ध लिखिये। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान प्रवृत्ति बहुकेन्द्रवाद की ओर है ?
Write an essay on 'Bipolarity and Polycentrism'. Do you agree with the view that the present trend is towards Polycentrism?
- 253 "यद्यपि विश्व बहुकेन्द्रीयवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, ध्रुवीकरण व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का आग्रह अभी भी बना हुआ है।" उपरोक्त कथन का विस्तार कीजिये तथा वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वभाव का परीक्षण कीजिये। (1976)
"Though the world is moving towards Polycentrism the main features of bipolar system still persist." Elaborate the above statement and examine the nature of International Politics at present.

- 254 "यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति धीरे-धीरे बहुकेन्द्रवाद की ओर अग्रसर हो रही है, किन्तु द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था (ध्रुवीकरण व्यवस्था) की मूल प्रवृत्तियाँ अभी भी बनी हुई हैं।" समझाइये। (1976)

"Though International Politics is gradually moving towards Polycentrism, the basic tendencies of the bi-polar system still persist." Discuss.

- 255 विश्व-राजनीति के द्वि-ध्रुवीयता के रूप में विकास का विवेचन कीजिये। इन दोनों में से विश्व-शान्ति के लिए कौन सी स्थिति अधिक अनुकूल है? (1981)

Bring out the evolution of World Politics from Bi-polarity to Multi-polarity? Which of the two is more conducive to maintain World Peace?

अध्याय-22 (अमेरिका-रूस-चीन सम्बन्ध)

- 256 "समकालीन विश्व-राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता है दो भीमकाय दैत्यों (रूस और अमेरिका) के बीच का संघर्ष।" व्याख्या कीजिये और समझाइए कि क्या यह कथन अभी भी सही है? (1977)

"The conflict between two monolithic giants the U.S.A. and the U.S.S.R. is the dominant reality of the contemporary World Politics." Explain Does it still hold good?

- 257 शीत-युद्ध के शैश्वर्य के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि क्या इसमें यह परिलक्षित होता है कि अमेरिका और रूस के हित मूलतः एक ही दिशा में उन्मुख हैं।

What are the primary reasons for the thaw in the Cold War and do you think it represents any basic convergence in U.S.-Soviet Interests.

- 258 "रूस तथा अमेरिका के सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति शान्तिमय प्रतिस्पर्धा की स्थिति है।" टिप्पणी कीजिये।

"Present State of Russo-American relations is of peaceful competitions" Comment.

- 259 1945 से 1982 तक सोवियत संघ के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश-नीति की विवेचना कीजिये।

Discuss the Foreign Policy of the U.S.A towards the U.S.S.R. from 1945 to 1982.

- 260 अमेरिका की साम्यवादी नीति सम्बन्धी नीतियों में वर्तमान में पाए जाने वाले परिवर्तनों के क्या कारण हैं? समझाकर लिखिए।

What are the reasons for the change in the U.S.A. towards Communist China in recent years.

- 261 पछ 10 वर्षों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सम्बन्धों का विवेचन कीजिये।

Discuss the relations between China and the U.S.A during the last ten years.

अध्याय-22 (अमेरिका-रूस-चीन-सम्बन्ध)

- 262 समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर चीन-सोवियत रूस विग्रह के प्रभाव की विवेचना कीजिए। (1980)

Discuss the impact of the Sino-Soviet rift on contemporary International Relations.

- 263 चीन और रूस के (अ) विचारधारा सम्बन्धी मतभेदों, तथा (ब) सीमा-विवाद के विषय में दृष्टिकोणों का विश्लेषण कीजिये। चीन-रूस संघर्ष के लिए उत्तरदायी वास्तविक कारण कौन से हैं? (1976)

Analyse the view-points of China and the Soviet Union on their (a) ideological differences, and (b) border disputes. What are the real factors responsible for Sino-Soviet Confrontation?

- 264 "चीन-रूस संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व का विस्तृत विवरण (या सत्यता बतलाना) आसान नहीं है। अपने अन्तर्राष्ट्रीय जीवन, न केवल स्वयं सोवियत युद्ध, के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है।" (जैड० के० ब्रेजेव्जिन्स्की)
उपरोक्त कथन को दृष्टि में रखते हुए चीन-रूस संघर्ष की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव की विवेचना कीजिये।

"It is difficult to exaggerate the historical significance of the Sino-Soviet conflict. It has influenced every fact of International life, not to speak of the Soviet Block itself" (Z. K. Brazezinski)

In the light of the above statement discuss the impact of the Sino-Soviet Conflict of International Politics.

- 265 चीन-रूस मतभेदों के मूल कारकों की विवेचना कीजिये।

Discuss the basic factors responsible for Sino-Soviet differences.

- 266 सोवियत संघ तथा चीन के आपसी विवाद के कारणों का उनके राष्ट्रीय हितों एवं सिद्धान्तों के सन्दर्भ में परीक्षण कीजिये। (1977)

Account for the Sino-Soviet Conflict with reference to the Ideology and national interest of these powers

- 267 "माओ की मृत्यु के उपरान्त चीन की घटनाओं ने यह अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है कि चीन-सोवियत झगड़े का सम्बन्ध दोनों देशों के नेतृत्व के बीच व्यक्तियों का संघर्ष मात्र न था।" समीक्षा कीजिए। (1978)

"Post-Mao developments in China have now proved beyond any shadow of doubt that Sino-Soviet Conflicts had very little to do with personality conflicts between the two leaderships of Soviet Union and China" Comments.

अध्याय-23 (अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव)

- 268 1945 के उपरान्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन तथा कार्य-संचालन में होने वाले मुख्य परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए।

Examine the main changes that have taken place in the organization and working of the United Nations since 1945.

- 269 सुरक्षा-परिषद के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसमें मतदान प्रणाली की विवेचना कीजिए। वीटो संयुक्त राष्ट्र के कार्यकरण को विरुद्ध रूप से कहाँ तक प्रभावित कर पाया है ?
Describe the composition and powers of the Security Council. Discuss the voting procedure. To what extent has the Veto adversely affected the working of the U. N.
- 270 "सुरक्षा-परिषद् का वास्तविक निष्प्रियता के रूप में पतन उसकी प्रियाओं के मर्यादक (मात्रात्मक) पतन तदनुसार महासभा की प्रक्रियाओं की वृद्धि से प्रमाणित (प्रदर्शित) होता है।" (इस जे० मार्गेंथो)
उपरोक्त कथन का विस्तारपूर्वक परीक्षण कीजिए। (1976)
"The decline of the Security Council to virtual impotence is demonstrated by the Quantitative Decline of its activities and the corresponding increase of those of the General Assembly." (Hans J. Morgenthau)
Elaborate and examine the above statement.
- 271 विश्व समस्याओं को हल करने के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन कीजिए।
Evaluate the United Nations as a means of solving world problems.
- 272 संयुक्त राष्ट्रसंघ की राजनीतिक गतिविधियों में उसके महासचिव की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।
Assess the role of the Secretary-General in the political activities of the United Nations.
- 273 संयुक्त राष्ट्र संगठन के संविधान में निषेधाधिकार सम्बन्धी प्रवन्ध के निर्माण, परिणाम तथा महत्त्व की चर्चा कीजिए।
Discuss the genesis, implications and significance of the 'Veto' provision of the U. N. Charter.
- 274 सद्यःपूर्ण वर्तमान विश्व राजनीति के सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता व उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। (1978)
Write a short note on the relevance of the United Nations Organization in the present day Conflict-ridden World Politics.
- 275 विश्वशान्ति और राष्ट्रों के बीच आर्थिक-सामाजिक समता को प्रोत्साहित करने में संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका पर प्रकाश डालिए। (1976)
Bring out the role of the United Nations in promoting World Peace and Socio-economic equality among Nations.
- 276 संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्षरत हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भूमिका की व्याख्या कीजिए। (1977)
Discuss the role of International Organizations like the U.N.O in harmonising conflicting interests in International Politics.
- 277 यूरोप अथवा मध्य-पूर्व के देशों में संयुक्त राष्ट्र शान्ति, व्यवस्था एवं न्याय बनाए रखने में कहाँ तक समर्थ हुआ है ? उनकी कुछ समस्याओं को क्यों अनसुना करने में छोड़ दिया गया है ? (1981)

How far has the United Nations been able to uphold peace, order and justice in European or Middle-East countries? Why have some of their problems been left unsettled?

- 278 संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधान में संशोधन में निहित विभिन्न मुद्दों का विवेचन कीजिए। (1980)

Discuss the various issues involved in the revision of U. N. Charter.

- 279 "संयुक्त राष्ट्रसंघ के ढाँचे में तात्त्विक परिवर्तन हो चाहिए।" आपकी दृष्टि में कौन-कौन से सुधारों की तत्काल आवश्यकता है? (1979)

"The United Nations Organization needs basic restructuring now." What reforms do you think it urgently needs?

- 280 विश्व-राजनीति के प्रचल में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। उनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन गया है? (1981)

Evaluate the impact of operation of various International Organisations of World Politics. In what way has the United Nations Organization become the most important of them?

- 281 सद्यपूरा वर्तमान विश्व राजनीति के सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता या सगति का परीक्षण कीजिए। (1981)

Examine the relevance of the United Nations Organization in the present day conflict-ridden world Politics.

- 282 "कुर्त वाल्दहीम के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर आज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है।" अपने विचार प्रकट कीजिए। (1979)

"U. N. O. under Kurt Waldheim wields more impact on International Politics now than it ever did". Present your own views on it.

- 283 अपने उद्देश्यों की पूर्ति में संयुक्त राष्ट्र कहीं तक सफल हुआ है? क्या आज इसके प्रसंविधान (चाटर) में संशोधन के ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिनमें वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन बन सके?

How far has the United Nations succeeded in realizing its objectives? Can you suggest any amendments to its charter which would make it a better instrument achieving its aim

- 284 "एशिया के विद्रोह और विरोधवादी के झगड़ों के सामने अटलांटिक चाट्टर, चार स्वतंत्रताओं और संयुक्त राष्ट्र के प्रखर वागदो धधुरे रह गये।" विवेचना कीजिए। (1980)

"The bright promises of the Atlantic Charter, the four freedoms and the United Nations were unfulfilled in the face of the quarrels of the victors and the revolt of Asia". Discuss.

अध्याय-24 (पश्चिमेशिया में समस्या-क्षेत्र और स्थितनाम)

- 285 पश्चिमी एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।

Discuss the factors which have influenced International Politics in West Asia.

- 286 नासिर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया की राजनीति का वर्णन कीजिए।
सादात की नीति का मूल्यांकन कीजिए।
Describe the Politics of West Asia crisis after the death of Nasir and the Policy of Mr. Sadat.
- 287 अरब-इजरायल संघर्ष के स्रोत की व्याख्या कीजिये। अरब-इजरायल सह-अस्तित्व का क्या आधार हो सकता है ? (1976)
Discuss the sources of Arab-Israel Confrontation. What may be the basis of Arab-Israel Co-existence ?
- 288 अरब-इजरायल संघर्ष के मूल में प्रमुख विवाद (समस्याएँ) क्या हैं ? इन विवादों का समाधान करने में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति कहां तक सफल रही है ? (1976)
What are the main issues at the root of the Arab-Israel Confrontation ? How far has the U. S. Foreign Policy been successful in solving these issues ?
- 289 इजरायल ने कैसे और क्यों युद्ध को अपनी राष्ट्रीय नीति का माध्यम बनाया है ? 1967 तथा 1973 के अरब-इजरायली युद्धों के सन्दर्भ में विश्लेषण कीजिए। (1977)
How and why has Israel made war as an instrument of National Policy ? Discuss with reference to the Arab-Israel wars of 1967 and 1973.
- 290 क्या आप यह मानते हैं कि पश्चिम एशिया में अपनी-अपनी परराष्ट्र नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति में अमेरिकी नेतृत्व सोवियत नेतृत्व से बाजी मार ले गया है ? यदि यही हुआ, तो कैसे ? (1978)
Would you say that in West Asia, the Americans have scored over Soviet Leadership in attaining their Foreign Policy objectives ? If so, how ?
- 291 क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि पश्चिमी एशिया में रूस की विदेश नीति का अन्त हो गया है ? अपने उत्तर के पक्ष में कारण तथा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। (1977)
Do you agree with the view that the Soviet Policy in West Asia has collapsed ? Give reasons and illustrations in support of your answer.
- 292 चीन-वियतनाम संघर्ष अथवा मार्च 1979 के मिस्र-इजरायली समझौते की प्रकृति तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। (1979)
Discuss the nature and consequences of the recent Sino-Vietnamese conflict or Egyptian-Israeli accords of March 1979.
- 293 वियतनाम की समस्या समझाइए। उसे सुलझाने में यू० एन० ओ० कैसे और क्यों प्रभावहीन रहा है ? (1981)
Discuss Vietnam Problem. How and why was U. N. O. ineffective in dealing with it ?
- 294 वियतनाम युद्ध की समाप्ति का दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की विदेश नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी विवेचना कीजिये।
Discuss the impact of termination of war in Vietnam on the Foreign Policies of the South-East Asia Countries.

- 295 "संयुक्त वियतनाम सैनिक ही नहीं, राजनीतिक तौर पर भी दक्षिण-पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी शक्ति है।" इस कथन के सन्दर्भ में ऐसी शक्ति के भारत के पड़ोस में स्थित होने से उसकी परराष्ट्र नीति के लिए क्या-क्या प्रश्न उठते हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। (1978)

"United Vietnam is politically no less than militarily, the most powerful State in South-East-Asia." In the light of this statement, bring out the implication of the presence of such a neighbouring power for India's Foreign Policy.

- 296 वियतनामी जनता की विजय और उनके देश के एकीकरण होने के बाद विशेष रूप से, दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमेरिका और चीन की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (1976)

Critically examine the role of the U. S. A. and China in South-East-Asia particularly after the Victory of Vietnamese people and unification of their country.

- 297 अमेरिकी-वियतनामी सशस्त्र संघर्ष की परिणति ने सामान्यतः विश्व-राजनीति पर, और विशेषतः दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति पर क्या असर डाला है? (1978)

How the resolution of American-Vietnamese armed conflict has affected the shape of World politics in general and S-E. Asian Politics in particular?

- 298 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर वियतनाम युद्ध के प्रभाव की परीक्षा कीजिए।
Examine the impact of Vietnam War on International Politics. (1978)

- 299 विवेचना कीजिए कि अफगानिस्तान की अभी हाल ही की घटनाओं ने पश्चिम एशिया की राजनीति को किस प्रकार और अधिक जटिल किया है। (1981)
Discuss how the recent development in Afghanistan have further complicated the West Asian Politics.

- 300 "अफगानिस्तान सोवियत वियतनाम नहीं है।" (एरिकसन) टिप्पणी कीजिए। (1981)
"Afghanistan is not Soviet Vietnam." (Erickson) Comments.

अध्याय-25 (पूर्वी यूरोप और हिन्द महासागर)

- 301 सोवियत संघ ने अपने पड़ोसी साम्यवादी देशों के साथ जिस ढंग के संबंधों का तानाबाना बुना है, उसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। (1979)
Discuss the salient features of pattern of relationship that the Soviet Union has forged with its Communist neighbouring states.

- 302 हिन्द महासागर को परमाणु मायुद्ध मुक्त क्षेत्र बनाने के पक्ष या विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (1978)
Argue out the case for or against making Indian ocean a Nuclear Free Zone.

- 303 हिन्द महासागर को 'परमाणु शस्त्र विरहित क्षेत्र' बनाने में क्या-क्या अड़चनें आ रही हैं ? इस सम्बन्ध में भारत की नीति की व्याख्या कीजिए । (1980)
What are the impediments in turning Indian Ocean into a 'Nuclear Free Zone.' Discuss India's position in this regard

अध्याय-26 (अन्य पहलू और नवीन घटनाचक्र)

- 304 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के किन्हीं पाँच नवीन घटनाचक्रों का उल्लेख कीजिए ।
Describe any five new events of International Politics.
- 305 नवीनतम राष्ट्रकुल सम्मेलन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए ।
Write a detailed note on the latest Conference of the Commonwealth of Nations.

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एवं टिप्पणियाँ

- 306 "साम्यवादी चीन आज की दुनिया की सबसे बड़ी और सर्वाधिक शक्तिशाली विलग्न शक्ति है ।" क्या आप इससे सहमत हैं ? अपने उत्तर के पक्ष में दलीलें दीजिये । (1979)
"Communist China is the present-day world's biggest and most powerful non-aligned country." Do you agree ? Give reasons in support of your position
- 307 "भारत के पड़ोसियों के सम्बन्ध में चीन की परराष्ट्र नीति शान्तिपूर्ण-सह-अस्तित्व पर आधारित नहीं मालुम देती है ।" विवेचना कीजिए । (1980)
"The Chinese Foreign Policy regarding India's neighbour is not a policy of peaceful co-existence " Comment.
- 308 अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका, सोवियत रूस तथा चीन के बीच एक त्रिकोणीय सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि आपकी राय में इस प्रकार का सम्बन्ध एशिया के लिए फायदेमन्द क्यों है ?
It is often said that there exists a triangular relationship between U.S.A , U.S.S.R. and China. How do you analyse this relationship and do you think this type of relationship is useful for Asia ?
- 309 बड़ी शक्ति और द्रष्टाकार शक्ति में क्या अन्तर है ? क्या विश्व-राजनीति के क्षेत्र में अमेरिका और सोवियत संघ के स्वरूप और भूमिका में कोई तात्त्विक अन्तर रहा है ? (1978)
How is a 'Super Power' different from 'Major Power' and are there any fundamental differences between the character and role of the two Super Powers, the U S A. and the U S S.R. in World Politics ?
- 310 "आधुनिक काल की तो भीमकाय शक्तियों के मध्य सघर्ष ही आधुनिक विश्व-राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है ।" इस कथन के प्रकाश में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य ग्राह्यपरिक तनाव के कारणों की विवेचना कीजिए । इस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है ?

"The conflict between the two monolithic giants of the Modern World is the dominant reality of the contemporary World-Politics." Discuss the main causes of the friction between United States of America and Union of Soviet Socialist Republic in the light of the above statement. How can this friction be made up?

- 311 संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य देता (तनाव-गंथिल्य अथवा समझौता एवं सहयोग) के आधार की विवेचना कीजिए। इन दोनों महाशक्तियों के मध्य व्यापक समझौते के मार्ग में कौन से कारक बाधक हैं?

Discuss the basis of 'detente' between United States and the Soviet Union. What are the factors preventing wider understanding between these two Super Powers?

- 312 क्या रूस-अमेरिका के वर्तमान सम्बन्धों की स्थिति को 'शान्तिमय प्रतिस्पर्धा' कहना उचित है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये। (1978)

Is it proper to say that the present state of Russo-American relations is that of 'Peaceful Competition'? Give arguments in support of your answer.

- 313 "विश्व राजनीति में जो दोनों महाशक्तियों-अमेरिका व सोवियत संघ को जोड़ता है, वह सब सार्विक रूप से उसकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो उन्हें विभाजित करता है।" अपनी विवेचना प्रस्तुत कीजिए। (1978)

"What unites the two Super Powers—the U.S.A. and the U.S.S.R. in World Politics is basically more important than what divides them." Give your comments on this statement.

- 314 "नाम्नवादी शक्तियों के बीच घन्टविरोधी की प्रकृति उस तरह की नहीं है जैसे पश्चिमी पूँजीवादी-साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच घन्टविरोध है।" इस कथन की समीक्षा कीजिए तथा अपने उत्तर का उदाहरणों से स्पष्टीकरण कीजिए।

"The nature of conflicts between the Communist Power is most similar to those between the Western Capitalist-Imperialist Powers." Discuss the statement and illustrate your answer with examples. (1978)

- 315 चीन और भारत के बीच सम्बन्धों की सामान्यीकरण और अंजपूर्ण बनाने की दिशा में से जाने में कौन-सी शक्तियाँ और तत्त्व बाधक हैं? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? (1978)

What are the forces and factors that come in the way of normalisation and warming up of Sino-Indian Relations? How can that be removed?

- 316 "तृतीय संसार के सैनिक शासन साम्राज्यवादी शक्तियों की सबसे अधिक विवक्षित अनुचर सरकारें पाबिन हुई हैं।" क्या तृतीय संसार के सभी सैनिक शासनों पर यह बात अच्छी तरह लागू होती है? (1978)

"Military regimes in the Third World have proved to be most reliable client states of the Imperialist Powers." It is correct characterisation of all such regimes in the Third World?

- 317 नई विश्व आर्थिक व्यवस्था की माँग की विवेचना कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं ? (1978)
Discuss the demand of a new world economic order. What attempts have been made in this direction during the last few years ?
- 318 "अब किसी तीसरी महती शक्ति के उदय के लिए कतई कोई जगह नहीं रह गई है।" विवेचना कीजिए। (1979)
"There is absolutely no room for the emergence of any more Super Power now." Discuss.
- 319 "दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास, अमेरिका व रूस का महानतम शक्तियों (Super Powers) के रूप में विश्व मंच पर उभरना है।" इस कथन को ध्यान में रखते हुए विश्व-राजनीति में इनकी भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। (1981)
"The most important development in the Post Second World War period is the emergence of the two Super-Powers, the U.S.A. and U.S.S.R. on the World scene." In the light of this statement discuss their different roles in World Politics.
- 320 नई आर्थिक विश्व-व्यवस्था के निर्माण के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों का विवेचन कीजिए। ये प्रयास क्यों असफल रहे हैं ? (1980)
Discuss the various efforts that have recently been made to achieve a new economic world order. Why have these efforts failed ?
- 321 कम्पूचिया के संघर्ष में चीन-वियतनामी विवाद की विवेचना कीजिए। भारत की नीति इसके संघर्ष में क्या रही है ? (1980)
Discuss the Vietnam-China dispute over Kampuchean problem. What has been India's position in this regard ?
- 322 अफ्रो-एशियाई शान्ति विषयक प्रश्नों पर चीन-सोवियत विवाद की विवेचना कीजिए। (1980)
Discuss the Sino-Soviet disputes as it relates to Afro-Asian problems of revolution.
- 323 क्या आप जनरल जिया उल हक के पाकिस्तान को एक विलम्ब देश मानते हैं और इस रूप में वह भारतीय उप-महाद्वीप में शान्ति का एक सम्भावित आधार बनकर उभर रहा है ? अपने विचार प्रकट कीजिए। (1980)
Do you consider Pakistan Gen Zia-ul-Haq a non-aligned country today and as such, a potential factor of peace in the sub-continent. Give your views.
- 324 "विश्व राजनीति में पूर्व-पश्चिम संघर्ष का स्थान धीरे-धीरे उत्तर-दक्षिण संघर्ष लेता जा रहा है।" क्या आप सहमत हैं ? अपने उत्तर के पक्ष में दलीलें तथा उदाहरण दीजिये। (1979)
"East-West conflict is being steadily replaced by North-South conflict in World Politics." Do you agree ? Give reasons and illustrations in support of your answer.

- 325 अफगानिस्तान अथवा चिलिस्तीन समस्या पर यू० एन० ए०, यू० एन० एन० एन० नया भारत के विदेश सम्बन्धी दृष्टिकोणों को बताइए। वे किस सीमा तक माय-माय चलने के लिए तैयार हैं ? (1981)
Account for the Foreign Policy preceptions of U. S. A., U. S. S. R. and India over Afghanistan of Palestine Problem. To what extent do they appear to go together ?
- 326 "आज अनेकों तनाव-क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की समस्याएँ नव-उपनिवेशवाद के कारण हैं।" क्या आप सहमत हैं ? अपने उत्तर के पक्ष में दलीलें तथा उदाहरण दीजिए। (1979)
"Large number of tension areas and problems of contemporary International Relations are due to neo-colonialism." Do you agree ? Give reasons and illustrations in support of your answer.
- 327 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखिए :— (1979)
Write short notes on any two of the following—
(अ) चीन-वियतनाम संघर्ष
(Sino-Vietnam conflict)
(ब) ईरान में हाल की घटनाएँ
(Recent events in Iran)
(ग) निक्सन सिद्धान्त
(Nixon doctrine)
- 328 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखिए— (1979)
Write short notes on any two of the following—
(अ) निक्सन सिद्धान्त
(Nixon Doctrine)
(ब) अणु शक्ति प्रसार निरोध सन्धि
(Nuclear Non-Proliferation Treaty)
(ग) साल्ट (SALT)
- 329 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :— (1980)
Write notes explaining briefly on any two of the following—
(i) रूस-चीन संघर्ष
(The Sino-Soviet conflict)
(ii) पलेस्टाइन की समस्या
(The Palestine Problem)
(iii) पश्चिम यूरोपीय एकीकरण
(Western European Integration)
- 330 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आलोचनात्मक तथु-निबन्ध लिखिए :— (1980)
Write critical notes on any two of the following—
(अ) लैटिन अमरीका की समस्याएँ
(Problems in Latin America)

(ब) बहु-केन्द्रवाद और 'देता' (तनाव-शैथिल्य)
(Poly-centrism and 'Detenta')

(स) भारत-चीन संघर्ष
(Sino-Indian conflict)

(द) संयुक्त राष्ट्र और विकासशील जगत्
(U. N. and the Developing World)

331 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए— (1980)
Write short notes on any two of the following—

(अ) ईरान में अमेरिकी बंधकों की समस्या
(The Problem of American Hostages in Iran)

(ब) पश्चिमी यूरोपीय राजनीति पर यूरो-साम्यवादी आन्दोलन का असर
(Impact of Euro-Communism on Western European Politics.)

(स) ओपेक राजनीति
(OPEC Politics)

332 निम्नलिखित कथनों में से किसी एक का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए— (1981)
Critically examine any one of the following statements—

(अ) "प्रयार्थवादी सिद्धान्त उन सभी तत्वों की उपेक्षा करता है जो साध्यों (Purposes) को प्रभावित या परिभाषित करते हैं।" (स्टेनले हाफमैन)
"The 'realist' theory neglects all the factors that influence or define purposes." (Stanley Hoffman)

(ब) "चूँकि मानव मस्तिष्क (मन) में ही युद्धों का जन्म होता है अतएव मानव मस्तिष्क में ही शान्ति की रक्षा-व्यवस्था निर्मित की जानी चाहिए।"
(अर्चिबाल्ड मैकलीश)
"Since it is in the minds of men that wars begins, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed."
(Archibald Macleish)

(स) "अन्य समाधानों की तुलना में सामूहिक सुरक्षा तथा शान्तिमय समझौते ही सामान्यतः शान्ति स्थापित करने के अधिक आशापूर्ण तरीके माने जाते हैं।" (पामर एवं पर्किन्स)
"Collective security and peaceful settlement of international disputes have been commonly regarded as the most promising of all the approaches to peace." (Palmer and Perkins).

333 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए— (1981)
Write short notes on any two of the following—

(अ) नामीबिया
(Namibia)

(ब) चीन-भारत संघर्ष
(Sino-Indian Conflict)

- (म) इस्लामिक अणु बम
(Islamic Atom Bomb)
(द) सुरक्षा-परिषद् की प्रतिनिधित्वता
(Representativeness of Security Council)

334 निम्नांकित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए— (1981)
Write short notes on any two of the following—

- (i) ईराक-ईरान संघर्ष
(Iraq-Iran Confrontation)
(ii) हिन्द महासागर और बड़ी शक्तियाँ
(Indian Ocean and Major Powers)
(iii) न्यूक्लियर हथियारों का प्रभाव
(Impact of Nuclear Weapons)
(iv) चीन-सोवियत संघर्ष
(Sino-Soviet Conflict)

335 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए— (1981)
Write short notes on any two of the following—

- (अ) एस० ए० एल० टी० (SALT)
(ब) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य की धारणा
(Concept of State in International Politics)
(स) यू० एस० ए० की आकाश-शटल
(Space Shuttle of U. S. A.)
(द) उत्तर-दक्षिण संवाद
(North-South Dialogue.)



ग्रन्थ-कोश

(BOOK-BANK)

-
- | | |
|---|--|
| 1. <i>Allen Henry C.</i> | : Great Britain and the U S |
| 2. <i>Acheson, Dean G</i> | : The Premises of American Policy. |
| 3. <i>Almond Gabriel A</i> | : The American People and Foreign Policy. |
| 4. <i>Acheson, Dean</i> | : Morality, Moralism and Diplomacy. |
| 5. <i>Adler, M.J.</i> | : How to think about War and Peace ? |
| 6. <i>Andrassy, J.</i> | : 'Uniting for Peace', American Journal of International Law. |
| 7. <i>Ascher, Charles S.</i> | : Programme-making in UNESCO; 1946-61. |
| 8. <i>Black and Thompson</i> | : Foreign Policies in a Changing World. |
| 9. <i>Bozeman, Adda B</i> | : India's Foreign Policy in Today's World Politics. |
| 10. <i>Bains, J S</i> | : India's International Disputes. |
| 11. <i>Benno, Wasserman</i> | : The Cultural and Psychological Approach to the Study of International Relations. |
| 12. <i>Burns, Arthur D, Carleton, William G</i> | : Ideology of Balance of Power. |
| 13. <i>Buebring, Edward H</i> | : Woodrow Wilson and the Balance of Power. |
| 14. <i>Brierly, J L.</i> | : 'From Balance to Deterrence', World Politics. |
| 15. <i>Barra Clough, Geoffrey</i> | : The Law of Nations. |
| 16. <i>Besterman Theodore</i> | : 'History, Morals and Politics' International Affairs, XXXIV. |
| 17. <i>Chakravarti, P. C.</i> | : UNESCO : Peace in the Minds of Men |
| 18. <i>Cohen</i> | : India-China Relations. |
| 19. <i>Colby C.C.</i> | : The Political Process and Foreign Policy. |
| 20. <i>Cobden Richard</i> | : Geographic Aspects of International Relations |
| 21. <i>Corbett, P E.</i> | : Political Writings. |
| 22. <i>Coplin, William D.</i> | : Law and Society in the Relation of States. |
| 23. <i>Corbett, Percy E</i> | : Introduction to International Politics. |
| 24. <i>Combon, Jules M.</i> | : Law and Diplomacy. |
| 25. <i>Chase Eugene P.</i> | : The Diplomatist. |
| 26. <i>Cheever, Daniel S & Haviland, H. Field, Jr</i> | : The United Nations in Action. |
| 27. <i>Coral Bell</i> | : Organizing for Peace : International Organisation in World Affairs. |
| 28. <i>Dr. H.V.P.</i> | : Negotiation from Strength. |
| 29. <i>Dallin Alexander</i> | : Chinese Foreign Policy, 1958-62. |
| 30. <i>Denisch, Karl W.</i> | : Soviet Conduct in World Affairs |
| 31. <i>Dickinson, Edwin D.</i> | : The Nerves of Government. |
| 32. <i>Dunn, F.S.</i> | : Law and Peace. |
| | : War and Minds of Men. |

33. *D.L.B. Hamlin* : Diplomacy in Evolution.
34. 'Diplomacy in Transition,' *Journal of International Affairs*.
35. *Eneny, Brooks* : Mainsprings of World Politics
36. *Eneny, Brooks* : The Strategy of Raw Materials
37. *Eagleton, Clyde* : Analysis of the Problem of War.
38. *Eagleton, Clyde and Swift, Richard N* : Annual Review of United Nations' Affairs.
39. *Eichelberger Clark* : UN-The First Ten Years.
40. *E.A.J. Johnson* : The Dimensions of Diplomacy.
41. *Fox, William T R* : Theoretical Aspects of International Relations.
42. *Fennick, Charles G.* : International Law, Appleton Century Crafts.
43. *Fox, William, T.R.* : National Interest and Moral Principles in Foreign Policy.
: The Reconciliation of the Desirable and the Possible.
44. *Foster, J W.* : The Practice of Diplomacy.
45. *Feller, A.H.* : United Nations and the World Community.
46. *Finer, Herman* : The United Nations' Economic and Social Council.
47. *Fred Charles Ikle* : How Nations Negotiate ?
48. *Govt. of India* : White Paper on India-China Relations.
49. *Gross Felix* : Foreign Policy Analysis.
50. *Gulick, Edward V* : The Balance of Power.
51. *Gulick, Leland M* : 'Korea : Collective Measures against Aggression,' International Conciliation No. 494.
52. *Goodrich, Leland M, and Simon, Anne P.* : The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security.
53. *Green, James Frederick* : The United Nations and Human Rights.
54. *Herman Kahn and Irwin Manne* : Game Theory, Washington
55. *Hoffman, Stanley* : Contemporary Theory in International Relations.
56. *Herz, John P.* : Political Realism and Political Idealism
57. *Haus, Ernest B* : The Balance of Power : Prescription Concept, or Propaganda World Politics.
58. *Haus, Ernest B* : Type of Collective Security : An Examination of Collective Concepts
59. *Hogan, Willard N.* : International Conflict and Collective Security : The Principle of Concern in International Organisation.
60. *Hawland, H Field Jr* : The Political Role of the General Assembly
61. *Holcombe, A N* : Human Rights in the Modern World
62. *Hamilton Fish Armstrong* : Neutrality : Varying Tunes.
63. *Ivo D. Duchacek* : Nations and Men : International Politics Today.
64. *Jacobson, H K* : America's Foreign Policy.
65. *Johnson, Howard C, Jr and Gerhart Niemeyer* : Collective Security : The Validity of an Ideal International Organisation VIII.
66. *Jessup, Philip C.* : International Security.

67. *Jimenez De Arechaga, Eduardo Jr* : Voting and the Handling of Disputes in the Security Council.
68. *James L. McCamy* : The Conduct of the New Diplomacy.
69. *Kerman, George* : Soviet Foreign Policy under Lenin and Stalin.
70. *Karunakaran, K P.* : India in World Affairs, 1947-50.
71. *Karunakaran, K P* : India in World Affairs, 1950-53.
72. *Kundra, T C* : Indian Foreign Policy, 1947-54.
73. *Kissinger, Henry A.* : The American Foreign Policy.
74. *Kaplan, Morton A* : System and Process in International Politics
75. *Keeton George W and Schwarzenberger* : Making International Law Work.
76. *Kelven, Hans* : The Law of the United Nations.
77. *Kelsen, Hans* : Principles of International Law.
78. *Lanterpacht, H.* : International Law and Human Rights.
79. *Leonard L, Larry* : International Organisation.
80. *Lie, Trygve* : In the Cause of Peace.
81. *Lester B. Pearson* : Diplomacy in World Politics.
82. *Lester B. Pearson* : Diplomacy in the Nuclear Age.
83. *Laurence W Martin* : Neutralism and Non-Aligement.
84. *Miller, J D B* : The Commonwealth in the World.
85. *Macridis, Roy C.* : Foreign Policy in World Politics.
86. *Macridis* : Readings in Foreign Policies.
87. *Morgenthau, Hans J.* : The Purpose of American Politics.
88. *Manning, C A.W.* : International Relations, Paris UNESCO.
89. *Miller, James G.* : Toward a General Theory for the Behavioural Sciences.
90. *McClelland, Charles A.* : Theory and the International System.
91. *Morgenthau, Hans J.* : In Defence of the National Interest.
92. *Morgenthau, Hans J.* : Scientific Man Vs. Politics.
93. *Maurice, A.* : World Politics.
94. *Morgenthau, Hans J* : Politics Among Nations.
95. *Mackinder, Sir Halford J.* : 'The Geographical Pivot' Geographical Journal, XXIII.
96. *Merriam, Charles* : 'Political Power' in a Study of Power History.
97. *Morgenthau, Hans J.* : National Interest and Moral Principles in Foreign Policy : The Primacy of the National Interest.
98. *Martin, Andrew* : Collective Security.
99. *Mitrany, David* : The Problem of International Sanction.
100. *MacLaurin, John* : The United Nations and Power Politics.
101. *Mitrany, David* : A Working Peace System : An Argument for the Functional Development of International Organisation.
102. *Mortimer, Molly* : Trusteeship in Practice.
103. *M A. Fitzsimons and Stephen D. Kertesz* : Diplomacy in a Changing World.
104. *Nehru, Jawaharlal* : India's Foreign Policy.
105. *Nagle, William J.* : Morality and Modern Warfare.
106. *Nicolson, Harold* : Diplomacy.

107. *Organski, A.F.K.* : World Politics.
108. *Oppenheim, Felix E.* : Dimensions of Freedom.
109. *Osgood, Robert E.* : Ideals and Self-Interest in America's Foreign Relations.
110. *Oppenheim, L.* : International Law.
111. *Palmer and Perkins* : International Relations.
112. *Panikkar, K.M.* : Principles and Practice of Diplomacy
113. *Percy, E. Corbett* : Law and Diplomacy.
114. *Peter Worsley* : The Third World.
115. *Padelford, Norman J and Lincoln, George A.* : International Politics : Foundations of International Relations.
116. *Pischke, Elmer* : International Relations, Basic Documents
117. *Quincy Wright* : A Study of War.
118. *Robinson, A.Z.* : The Foreign Policy of the Soviet-Union.
119. *Rostow, W.W.* : The United States in the World Arena
120. *Rajan, M.S.* : India in World Affairs.
121. *Rosenbaum, Naomi* : Readings in the International Political System
122. *Russell, Bertrand* : Power, A New Social Analysis.
123. *Roosevelt, Eleanor, and De Witt, W.A.* : U.N.—Today and Tomorrow
124. *Reinsch P* : World Politics.
125. *Snyder, Richard C., H.W. Bruck and Burton Sapin* : Foreign Policy Decision Making. An Approach to the Study of International Politics
126. *Sprout, Harold and Margaret* : Foundations of National Power.
127. *Stanley Eugene* : Raw Materials in Peace and War.
128. *Schwarzenberger, George* : Manual of International Law.
129. *Smith, H.A.* : The Crisis in the Law of Nations
130. *Steven Rosen and Walter Jones* : The Logic of International Relations.
131. *Savard, Ruth Compiler* : American Agencies Interested in International Affairs
132. *Schleicher, Charles* : Introduction to International Relation
133. *Schuman, Frederick L* : International Politics : The Western State System in Mid-Century.
134. *Schwarzenberger, George* : Power (Politics : A Study of International Society
135. *Sharp, W. and Kirk, Grayson* : Contemporary International Politics
136. *Simonds, Frank H. and Emery Brooks* : The Great Powers in World Politics.
137. *Steiner, H. Arthur* : Principles and Problems of International Relations
138. *Stamer-Hage, Robert and Possony, Stefan* : International Relations In the Age of the Conflict between Democracy and Dictatorship.
139. *Thompson, Kenneth, W* : The Study of International Politics
140. *Thompson, Kenneth W* : Christian Ethics and Dilemmas of Foreign Policy
141. *Trivers Haward* : Morality and Foreign Affairs.
142. *Thompson, Kenneth H* : "Collective Security Re-examined " American Political Science Review.
143. *Tew, Brian* : International Monetary Co-operation
144. *United Nations' Publications* : Yearbook of the United Nations.

145. UNESCO : International Reports of Social Documentation Centres.
146. Virginia Quarterly Review XXXIII
147. *Vannever Bush* : Modern Arms and Freedom.
148. *Vandenbosch, Army and Hugan Willard N* : The United Nations Background Organisation, Function, Activities.
149. *Werner Devis* : Modern China's Foreign Policy.
150. *Wolfers, Arnold* : Discord and Collaboration.
151. *Wolfers, Arnold and Martin Laurence, W* : The Anglo-American Tradition in Foreign Affairs.
152. *Wright Quincy* : Contemporary International Law: A Balance Sheet.
153. *Wolfers Arnold* : "Statesmanship and Moral Choice." World Politics
154. *Weldon, T.D.* : States and Morals: A Study in Political Conflicts.
155. *Wolfers, Arnold* : "Collective Security and the War in Korea", The Yale Review XLIII.
156. *Webster, Sir Charles* : The Art and Practice of Diplomacy.
157. *Waters, V. Orval* : The United Nations: Planned Tyranny.
158. *Witte, Lyman C.* : International Non-Government Organisations: Their Purposes, Methods and Accomplishments
159. *Wightman, David* : Economic Co-operation in Europe.
160. *Wilcox, Francis O. and Marcy, Carl M* : Proposals for Changes in the United Nations.
161. *Welsh E.A.* : The History and Nature of International Relations.

Periodicals, Journals & Dailies

- | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Current History. | 2. Foreign Affairs. | 3. Asian Survey. |
| 4. Link. | 5. Diplomat | 6. Journal of Asian Studies |
| 7. Journal of Politics | 8. Pacific Affairs | 9. World Politics. |
| 10. International Affairs. | 11. Review of Politics | 12. International Studies. |
| 13. India Quarterly. | 14. Hindustan Times. | 15. Navbharat. |
| 16. Hindustan. | 17. Span. | |

